111151

111151

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६० अंक १३
१५ जुलाई, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
टना : विकास कुमार झा
संवाददाता
नखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
तोपाल : सुधीर सक्सेना
ायपुर : ओम सैनी
ला निदेशक
दु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ न : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ तस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३१४७९३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, खनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना र्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, पाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ न : ६६३८८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन ट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, लेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता न : २९९०३५ जयपुर कार्यालय : ए-२०, शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर-४. फोन : ४८१९५

r surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, mapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, hillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. or Agartala, it is 25 paise.

©

स अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

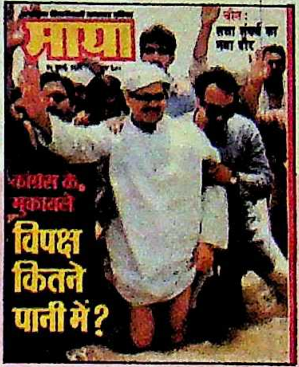

MAYA 1989

111151 ~~२१~~ ⑧ L. Pt II

चीन
चीन में छात्र आंदोलन को कुचलने का परिणाम क्या होगा ? ६६

कैप्टन शामजी
गुजरात
पुलिस के लिए पहेली बना शामजी आखिर कौन है ? १७

आवरण कथा

राज्यों के घमासान दौरे, पंचायत राज और नेहरू रोजगार जैसी मोहक योजनाओं का प्रचंड प्रचार और दूरदर्शन के जरिये विपक्ष पर धुआंधार हमले करके कांग्रेस ने अपना आक्रामक चुनाव-अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की इस चुनावी पहल और व्यूह रचना के जवाब में विपक्ष क्या कर रहा है ? क्या वह कांग्रेस का मुकाबला करने की स्थिति में है ? क्या जनता दल ने अपना 'गृहयुद्ध' समाप्त कर लिया है ? कांग्रेस की चुनाव-रणनीति क्या है ?

बिहार
बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह तथा तारिक अनवर के तालमेल का मकसद क्या है ? ५४

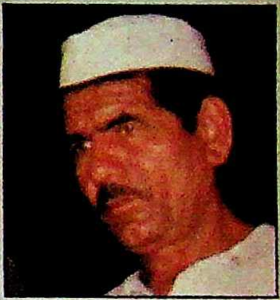

उत्तर प्रदेश
अलीगढ़ जिले में किसानों पर गोली चलाने की नौबत क्यों आयी ? ४६

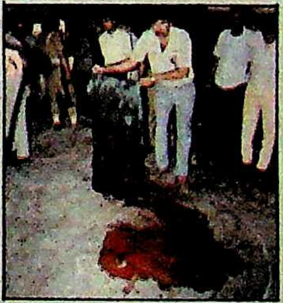

दिल्ली बमकांड
दिल्ली में रेड अलर्ट के बावजूद आंतकवादी नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट करने में कैसे सफल हुए ? २६

राजस्थान
मंत्रिमंडल में हाल ही हुए नये उलटफेर से क्या प्रदेश के असंतुष्ट कांग्रेसी संतुष्ट हो जायेंगे ? ५०

दिल्ली दरबार : गुप्तचर माहात्म्य १०
फोटोफीचर १३
खोजखबर : जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय : बखेड़ों के जाल में २१
विवाद : राजभाषा समिति : हिंदी के साथ फिर सौतेला सलूक ४४
राजस्थान : बाल रश्मि सोसायटी : समाजसेवी संस्था पर सियासी कहर ४८
राजस्थान : सांप्रदायिकता का नया चेहरा ५२
मप्र : न्यायपालिका को श्रमिक नेता की चुनौती ५९
दुनिया ७३
अभिमत : सुरेंद्र मोहन ७६
प्रसंगवश : बहुपत्नी प्रथा : धर्म के परदे में ७९
बेढब ८१
प्रसंगवश : बहराइच अग्नि कांड : आरिफ का जनहित अभियान ८२
फिल्म : उड़िया फिल्मों का पतन क्यों हो रहा है ? ८३
अर्थतंत्र : महाकोला की भिड़ंत पेप्सीकोला से ९०
स्त्री : चाहिए एक आदर्शवादी रिमोट कंट्रोल ९२
परदे के पीछे ९३
दूरदर्शन ९५
लोग ९६

आवरण पारदर्शी
गिरीश श्रीवास्तव

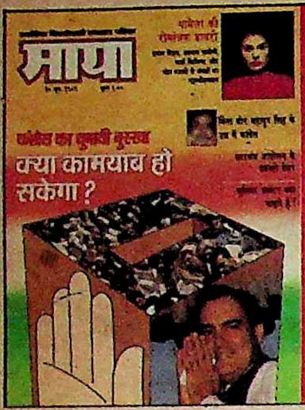

कांग्रेस का चुनावी नुस्खा क्या कारगर हो सकेगा ?

३० जून की 'माया' मिली। एक बैठकी में पूरी 'माया' पढ़ डाला। इसमें दो राय नहीं कि 'माया' सही समय पर सही जगह चोट करती है। अबकी ही देखिए, उसे यह लगा कि आम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो उसने कांग्रेस के चुनावी नुस्खे पर ही ध्यान केंद्रित करवा दिया पाठकों का। 'माया' का यह अनुमान कि इस बार स्थिति १९६७ जैसी होगी यानी जनता सोच-समझकर अपने मत का प्रयोग करेगी—हो सकता है सही हो, लेकिन मुझे भारतीय जनमानस की प्रवृत्तियों को देखकर ऐसा नहीं लगता। यहां की जनता तो ऐसी है कि यदि राजीव गांधी के परिवार पर पुनः कोई संकट आ जाये और वह अपने सरकारी डिब्बे पर उसका प्रचार करने लगें, तो समझिए राजीव गांधी पुनः निष्कंटक-रूप से सत्ता पर काबिज हो जायेंगे। हां, यह हो सकता है कि अबकी कांग्रेस को कोई नारा न मिले। लेकिन कांग्रेसी इतने चालाक हैं कि वे पंचायती राज का बाजा बजाना शुरू कर दिये हैं। यह भी संभव है कि ३१ अक्तूबर को चुनाव हों, ताकि इंदिरा गांधी के नाम पर जनता की भावनाओं का फिर शोषण किया जा सके। दूसरी ओर विपक्ष की जो नाजुक स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए तो कांग्रेसियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि अपनी असफलताओं की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। हमारे प्रधानमंत्री तो टीवी पर इतने उत्साहित नजर आते हैं कि एक-एक न्यूज बुलेटिन में तीन-तीन बार भाषण देते दिखायी देते हैं। टीवी न हुआ, कांग्रेस का चुनावी डिब्बा हो गया! इस समय आदिवासियों-जनजातियों-महिलाओं और नवयुवकों पर तो इतने मेहरबान हैं कि दोनों हाथों योजनाएं लुटा रहे हैं। **—एसके शुक्ला, १८ साल्ट लेक लेन, कलकत्ता**

बूटा सिंह की घेरेबंदी

१५ जून, १९८९ की 'माया' में गृहमंत्री बूटा सिंह पर आधारित आवरण कथा पढ़ी। राजनीति के ज्वार-भाटे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विश्वस्त सलाहकार के रूप में अडिग रहने वाले बूटा सिंह के बारे में इतनी बातें जानकर खुशी हुई।

देश की एकता-अखंडता के प्रति सदैव मर मिटने को तैयार बूटा सिंह पर जो विपक्षी आरोप लगाते हैं, वे बेमानी से जान पड़ते हैं। गोरखालैंड, असम, पंजाब या बाबरी मस्जिद संबंधी जो समस्याएं हैं, वे अकेले बूटा सिंह के कारण हैं, कहना ठीक नहीं। इंदिराजी के तो वे निकट रहे ही, यदि राजीव गांधी की कृपादृष्टि भी उन पर बनी रही, तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। **—'तनहा' नागपुरी, द्वारा बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र**

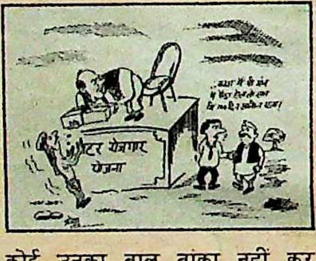

बूटा सिंह ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि वे अब तक आठ-दस मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना इतना आसान नहीं जितना यह कह देना आसान है कि वे मुख्यमंत्रियों को बदल सकते हैं। चुरहट लाटरी कांड के फैसले के बाद अर्जुन सिंह को हटाकर नया मुख्यमंत्री चुने जाने में पूरे दो दिन लग गये थे। गृह मंत्री बूटा सिंह और माखन लाल फोतेदार के अलावा गुलाम नबी आजाद, दरबारा सिंह जैसे दिग्गजों के रहते प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री को सत्ताच्युत करने में पसीने छूट गये थे। जब मुख्यमंत्री को बदलने में पूरा केंद्र जुटा था, तब यह कैसे माना जाये कि अकेले बूटा सिंह आठ-दस मुख्यमंत्री बदल चुके होंगे? **—दादूराम सलौने 'चौकन्ना', रीवा रोड, सतना**

नकली दवाओं का पनपता कारोबार

१५ जून की 'माया' में 'नकली दवाओं का पनपता कारोबार' में व्यक्त लेखक के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने वर्तमान दवा-बाजार का वास्तविक चित्रण किया है। कमोबेश यही स्थिति हर राज्य में है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है।

जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्राहक को लूटने में कसर नहीं छोड़तीं, तो भला ये छोटी-मोटी कंपनियां क्यों पीछे रहेंगी? **—सुनील रामनानी, सिंधी कालोनी, नीमच, मप्र**

'माया' का ताजातरीन अंक (१५ जून) पढ़ा। इस अंक में 'नकली दवाओं का पनपता कारोबार' पढ़ा। राज्य सरकार शायद गैरकानूनी तथा जल्द-से-जल्द पैसा बनानेवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसका परिणाम तो उस समय सामने आयेगा, जब मौत तांडव नृत्य कर चुकी होगी। **—जितेंद्र सी जैन, विट्ठलवाड़ी, बंबई-२**

खेल-खेल में विवाह

'माया' ने १५ जून के अंक में 'खेल-खेल में विवाह' के माध्यम से राजस्थान में चल रही कुप्रथाओं का सही चित्र खींचा है। सचमुच ही सामाजिक परंपराओं के नाम पर इस प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा देने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा इस प्रकार के विषवृक्ष उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। **—संजीव सराफ, पद्माकरनगर, मकरोनिया, सागर**

विपक्ष जन समर्थन खो रहा है

१५ जून की 'माया' में डा० जय दुबाशी द्वारा व्यक्त विचार कि विपक्ष तेजी से अपना जन-समर्थन खो रहा है, सत्य लगा। नेताओं के जमघट ने विपक्षी दलों को अपनी आंतरिक प्रतिस्पर्धा में ही उलझा दिया है। सब समेटने एवं धर्मनिरपेक्षता का आव ओढ़ने के चक्कर में जनता दल पूरी त दलदल नजर आने लगा है। अके भाजपा जरूर अपने सुदृढ़ संगठन के ब पर शौर्य का प्रदर्शन करना चाहती है लेकिन विपक्षियों के चक्कर में लगता वह भी सफल न हो पायेगी। **—आन शर्मा, भीलवाड़ा, राजस्थान**

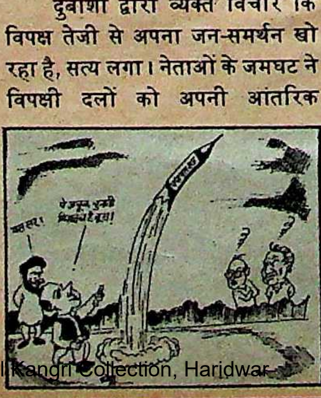

वास्तव में भारतीय जनमानस का य दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस मुकाबले समर्थ व शक्तिशाली विप आज तक नहीं उबर सका। विभाजित असंगठित विपक्ष का पूरा लाभ कांग्रे को मिलता रहा है और अल्पमत उपरांत भी वह सत्ता हथियाने में सफ होती रही है। जनता दल के उदय साथ यह आशा बंधी थी कि भ्रष्ट अयोग्य कांग्रेस सरकार अब कुछ माह ही मेहमान है, लेकिन इसके नेताओं आपसी खींचतान तथा चंद्रशेख सुब्रह्मण्यम स्वामी, देवगौड़ा आदि भितरघातों के कारण अब यह स्व प्रतीत होने लगा है। ऐसा आभास हो है कि भारत की निरीह जनता कांग्रेस अक्षम, अकुशल व भ्रष्ट शासन भोगने के लिए अभिशप्त है। **—सु साह, लोदी रोड, नयी दिल्ली**

भारत की छीछालेदर उत्तरदायी कौन ?

१५ जून की 'माया' में 'वेस्टइंड दौरा: भारत की छीछालेदर उत्तरदायी कौन ?' पढ़ा। आपने अ कारण दिये हैं जिनके चलते छीछाले हुई है। इसके अलावा भी कुछ कारणों पर मैं आपका ध्यान आ करना चाहता हूं। हार का मुख्य का भारतीय टीम में आत्मविश्वास की तथा श्रीकांत की अनुपस्थिति र इसके अलावा प्रशिक्षण, अभ्यास बोर्ड द्वारा चयन दोषपूर्ण एवं पक्षपात दिखायी दे रहा था। वेंगसरकर कप्तानी के सभी गुण भी न निम्नलिखित बातों पर अगर दिया जाये, तो शायद दुबारा छीछा की नौबत न आये: (१) टीम योग्यता के अनुसार भरती की जा कि सिफारिश के आधार पर। अच्छा प्रदर्शन न करनेवाले खिला लिए सज़ा की व्यवस्था की ज (३) आल राउंडरों को टीम में शा किया जाये। (४) स्पिनर की अ

स्ट बालरों को वरीयता दी जाये। ५) टीम में पतले-दुबले खिलाड़ियों की क्षा मजबूत शरीरवालों को वरीयता । (६) टीम का चयन कप्तान की र्जी को देखते हुए करें। **—राजीव मार वर्मा, इटावा, उप्र**

रदर्शन : कितना पास कितना र ?

रदर्शन आज आम दर्शकों से दूर होता जा रहा है। मंडी हाउस के गलत ये के कारण घटिया एवं सतही रावाहिकों की भरमार हो गयी है। ले रविवार को लोग टीवी सेट से पके रहा करते थे, आज वे ही दर्शक र्फ 'महाभारत' धारावाहिक देखकर ी सेट बंद कर देना ज्यादा पसंद ते हैं, क्योंकि दूरदर्शन पर बोर होकर ना रविवार कोई क्यों खराब करे? हास, विज्ञान एवं देशभक्ति का पाठ ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ुति रोचक होनी चाहिए न कि झल।

दूरदर्शन समाचार वाचकों का वारण दोष भी बहुत खलता है। वे केरल को केरला, कर्नाटक को कर्नाटका, मेघालय को मेघालया, कलकत्ता को कैलकटा तो कहते ही हैं, व्यक्ति विशेष के नामों का भी विकृत उच्चारण करते हैं, जैसे सर्वश्री प्रेमदास को प्रेमदासा, जयवर्द्धने को जयवर्द्धना, एसआर बोम्मई को बोमाई तथा ज्योति बसु को बोसू इत्यादि। इस प्रकार की गलतियां बार-बार दोहरायी जा रही हैं। यह सब किस मानसिकता का परिचायक है? **—गोपालजी सहाय, बरौनी उर्वरक-नगर, बिहार,**

जरूरत है आंदोलन छेड़ने की

'फिल्म' स्तंभ के अंतर्गत कला फिल्मों के बारे में पढ़ा। अत्यधिक धन-लिप्सा एवं व्यावसायकि होड़ के चलते हमारे फिल्म निर्माता एक ऐसा माहौल तैयार कर चुके हैं जिसके साये तले यथार्थवादी (कला) फिल्मों का भविष्य मृतप्राय सा हो गया है। महज सतही भाव-भंगिमाओं, अशोभनीय देह-दर्शन का आदी को चुका हमारा आम सिनेदर्शक गंभीर व सोद्देश्य फिल्मों का अवलोकन कर पाने में स्वयं को असमर्थ सा पाता है।

इस दुखद रुचि परिवर्तन हेतु एक सार्थक, सतत एवं शक्तिशाली वैचारिक आंदोलन छेड़ना होगा जिसके तहत निर्माता—निर्देशकों, वितरकों, फिल्म फाइनेंसरों, सिनेमालिकों एवं अभिनय-कर्मियों को एकजुटता प्रदर्शित करनी होगी। **—प्रदीप पालीवाल, गांधी मार्केट, इटावा, उप्र**

टूटे सपनों की आहत आंखें

'माया' का जून प्रथम अंक मिला। श्रीमती ममता कालिया का लेख 'टूटे सपनों की आहत आंखें', पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि हमारे देश में बच्चों की किस हद तक हीन दशा हो गयी है। बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक तरफ हमारे देश के नेता एवं राजनीतिज्ञ बच्चों की दशा को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की बाल-विकास योजनाएं बनाते हैं एवं बच्चों के चहुमुखी विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने के बाद वे सारी योजनाएं भूल जाते हैं। इसलिए हमारे देश की जनता एवं युवावर्ग को नेताओं एवं सरकार के भरोसे पर नहीं टिके रहना चाहिए। बच्चों की हीन दशा को सुधारने के लिए देश के युवावर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। **—गिरीश कुमार, सुगर फैक्ट्री, बाजपुर, नैनीताल**

निवेदन

'माया' अयाचित सामग्री स्वीकार नहीं करती है। अयाचित सामग्री के साथ समुचित डाक टिकट लगा लिफाफा नहीं होगा, तो उसे लौटाने की जिम्मेदारी भी 'माया' की नहीं होगी।—संपादक

चेतावनी

ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग अपने को 'माया' का प्रतिनिधि/संवाददाता बताकर अधिकारियों और आम लोगों से संपर्क करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। इसलिए 'माया' के नाम से मिलने वाले व्यक्ति का परिचय-पत्र अवश्य देखें और संशय की स्थिति में इलाहाबाद मुख्यालय या राज्यों की राजधानियों में स्थित हमारे कार्यालयों को सूचित करें।

—संपादक

खयालात

राम से बनी है, ब्रांडी ब्रह्मा से ह्विस्की विष्णु से। **राज्यमंत्री कुमार मणोत, भोपाल (विस) में।**

पृथ्वीराज और जयचंद भांति एक दूसरे का गला काटने तुले दोनों ठाकुरों (वीपी सिंह चंद्रशेखर) को यह नहीं भूलना हुए कि एक मुहम्मद गोरी दोनों खतम करने के लिए घात लगाये है। **—मधु लिमये, 'संडे मेल'**

धी दल और प्रतिबद्धता? भव, वे स्वयं के लिए भी प्रतिबद्ध हैं—उनका नेतृत्व तो हमारी के भगोड़े कर रहे हैं। **—केके री, 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ या**

व गांधी अब अपने हेलीकाप्टर ड़कर राज्य विधानसभाओं के के ऊपर से गुजरते हुए सीधे में पहुंच जाना चाहते हैं। **—मधु ते**

कतई नहीं चाहते कि इन दिनों जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी कारी राजीव गांधी और भाई अंबानी को मिले। **ीलाल**

देवीलाल

अर्चना पूरन सिंह

मैं समूची कांग्रेस पार्टी को एक हाथ से धूल चटा देने में सक्षम हूं। **—अरुण नेहरू, 'प्रोब इंडिया'**

अगर मैं बलराम जाखड़ होता, तो खुदकुशी कर लेता। **—राम जेठमलानी, 'इंडियन एक्सप्रेस'**

एक ओर आंध्र प्रदेश की जनता सूखे और पेयजल संकट से जूझ रही है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री रामाराव विश्वामित्र बनकर मेनका के साथ नाच रहे हैं। **—राजीव गांधी, तिरुपति में**

दरअसल राजीव गांधी की इमेज (छवि) अब खलास हो चुकी है—वे ईमानदारी और निष्ठा से कोई काम करना भी चाहें, तो सहसा लोग भरोसा नहीं करेंगे। **—चिमनभाई मेहता, 'विनमान'**

हमारा युद्ध का मोर्चा कांग्रेस-इ है, यह पार्टी (जनता दल) तो हमारा शांति का मोर्चा है। **—विश्वनाथ-प्रताप सिंह**

जवाहर रोजगार योजना चुनावों के बाद अपने आप मर जाये, तो कोई अचरज की बात नहीं। **—ज्योति बसु**

जनता दल से हमारे चुनावी तालमेल की संभावना चाहे जो भी हो, भाजपा भावी प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को ही पेश करेगी। **—लालकृष्ण आडवाणी, पालमपुर में**

इन दिनों वे (वीपी सिंह) बदहवासी की मानसिकता में हैं, यह उनके सूने (उदास) चेहरे से जाहिर हो जाता है। **—माखनलाल फोतेदार, 'हिंदुस्तान टाइम्स'**

यह अमानुषिक कार्रवाई (बीजिंग में निहत्थे लोकतंत्रवादियों पर गोलीबारी) जलियांवाला बाग कांड को भी लजा देनेवाली थी। **—वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य (साहित्य अकादमी अध्यक्ष), दिल्ली**

'जेट-सेट' जीवन-शैलीवाले महानगरों में यदि कोई यह दावा करता है कि शादी के पहले उसके गलत सेक्स-संबंध नहीं रहे हैं, तो मेरा खयाल है, यह एक बेहूदगी भरा झूठ होगा। **—अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, 'टीवी एंड वीडियो वर्ल्ड'**

◆

देश

१ जून : जनता दल-भाजपा के बीच लोकसभा चुनावों के लिए तालमेल का आधार तय।

२ जून : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के परिवहन राज्यमंत्री धर्मवीर सिंह का विधानसभा से निर्वाचन रद्द, छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। हरियाणा जनता दल के विधायक रघुयादव अनुशासनहीनता के आरोप में ५ वर्ष के लिए दल से निष्कासित।

३ जून : अखिल बोडो छात्र संघ और बोडो जन संघर्ष समिति द्वारा २६ जून से ३४० घंटे के असम बंद की घोषणा। सरकार द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के २१७ जूनियर डाक्टर बर्खास्त।

४ जून : ७९ वर्षीय प्रसिद्ध कमेंट्रेटर तथा न्यूजरीडर मेलविल डिमेलो का नेशनल हार्ट फाउंडेशन अस्पताल में निधन।

५ जून : चांदीपुर (उड़ीसा) से जमीन से जमीन पर मार करने वाला भारतीय मिसाइल 'त्रिशूल' सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। आंध्र प्रदेश कांग्रेस-इ के विधायक पी जनार्दन रेड्डी और दामोदरी रेड्डी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित।

६ जून : देश में श्वेत क्रांति के प्रणेता व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डा० वर्गीज कुरियन को वर्ल्ड फूड पुरस्कार।

७ जून : हीरालाल देवपुरा राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित। केंद्र सरकार झारखंड आंदोलन के नेताओं से क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर संविधान को मद्देनजर रखते हुए बातचीत को तैयार।

८ जून : राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत सहित १३ नये मंत्री शामिल।

९ जून : झारखंड बंद के दौरान रांची, सिंहभूम और छोटानागपुर में व्यापक हिंसा, ३५१ 'बंद' समर्थक गिरफ्तार।

१० जून : भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना से गठबंधन करने का फैसला।

११ जून : भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा रामजन्मभूमि बहुसंख्यक समुदाय के हवाले करने का सरकार से आग्रह।

१२ जून : जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह से इस्तीफे की मांग करके अनुशासन भंग करने के आरोप में जनता दल नेता हरिकेश बहादुर, बल्लभ भाई और छगनभाई को कारण बताओ नोटिस। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भयानक बम विस्फोट, ८ व्यक्ति मृत, ५३ बुरी तरह घायल। ३० जुलाई तक शांति सेना को वापस बुलाने का श्रीलंका सरकार का प्रस्ताव भारत द्वारा नामंजूर।

१३ जून : असम के पूर्वमुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया राज्यसभा के चुनाव में पराजित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन गुट द्वारा झारखंड इलाके में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम वापस।

१४ जून : नजरबंद नेता प्रकाश सिंह बादल को अकाली दल (तलवंडी) ने पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना। पीटर लिन सिनई आस्ट्रिया में, रोमा मजूमदार डेनमार्क में, कुशल बकुला मंगोलिया में, सुरिंदरलाल मलिक हंगरी में भारत के नये राजदूत नियुक्त।

१५ जून : सरकार द्वारा साढ़े तीन हजार हड़ताली डाक्टर बर्खास्त। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री डा० कर्ण सिंह अमरीका में भारत के नये राजदूत।

अशोक गहलोत

डा० कर्ण सिंह

सोसुके उनो

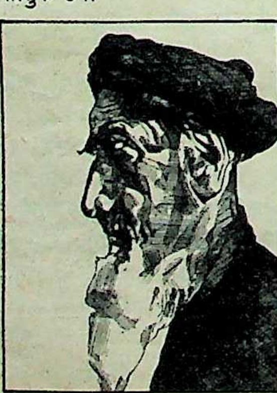

अयातुल्लाह खुमैनी

विदेश

१ जून : श्रीलंका के राष्ट्रपति राणासिंघे प्रेमदास द्वारा भार सरकार से भारतीय शांति सेना को जुलाई के अंत तक वाप बुलाने का आग्रह। फिलीपींस में सोने की खानोंवाले इलाके भारी वर्षा से सुरंग धंसी, १६५ व्यक्ति मृत।

२ जून : जापान के विदेश मंत्री सोसुके उनो जापान प्रधानमंत्री बने।

३ जून : श्रीलंका में भीषण वर्षा के कारण बाढ़, ३०० आद मरे, लाखों बेघर। ईरान में इस्लामी क्रांति के नायक ८७ वर्षी अयातुल्लाह खुमैनी का निधन।

४ जून : सोवियत संघ में गैस पाइप लाइन फटने से दो ट्रेनों आग लगी, १२०० लोग मरे। चीनी सेना द्वारा थ्येन आन म चौक में अंधाधुंध गोलियां चलाने से ३,००० छात्र व नागरि मरे।

५ जून : पोलैंड में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहले लोकतांत्रि चुनाव में मजदूर संगठन 'सालिडेरिटी' को स्पष्ट बहुम अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा लोकतंत्र समर्थक छ आंदोलन को कुचलने के कारण चीन सरकार के विरोध सैनिक साज-सामान की बिक्री और व्यावसायिक निय स्थगित करने का आदेश।

६ जून : सोवियत संघ के उजबेकिस्तान गणराज्य में जारी द में ५० व्यक्ति मरे। फ्रांस द्वारा चीन की सैनिक कार्रवाई विरोध में चीन से सभी राजनीतिक संपर्क समाप्त, ब्रिटे स्विट्जरलैंड द्वारा चीन को हथियारों की बिक्री पर रोक

७ जून : अफगानिस्तान में सेना और मुजाहिदीनों के म लड़ाई में ६०० व्यक्ति मरे।

८ जून : सोवियत संघ का मिग-२१ लड़ाकू विमान हव प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। नेपाल सरकार द्वारा भारत पत्रिका 'धर्मयुग' पर प्रतिबंध। ईरान की संसद के अध्यक्ष अ सेना प्रमुख हाशमी रफसनजानी द्वारा राष्ट्रपति पद के लि अपने नाम की घोषणा।

९ जून : यूनान के प्रधानमंत्री ओंद्रे पापेंद्रू द्वारा अपनी पत मारग्रेट को तलाक।

१० जून : सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई रिझकोव द्वा मंत्रिमंडल का नये सिरे से गठन।

११ जून : अमरीका के टेनिस खिलाड़ी माइकल चांग ने स्टीफे एडबर्ग को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों एकल खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता नेल्स मंडेला 'गद्दाफी मानवाधिकार' पुरस्कार से सम्मानित।

१२ जून : कनाडा के तेज धावक बेन जानसन द्वारा विश्व तेज धावक बनने के लिए जानबूझ कर प्रतिबंधित दवाओं सेवन करने की बात स्वीकार।

१३ जून : जापान के नये प्रधानमंत्री सोसुके उनो पर गी (नर्तकी) से संपर्क होने का आरोप, जापान की विपक्षी पार्टि द्वारा त्यागपत्र की मांग। दिवंगत अयातुल्ला खुमैनी के १०० वर्षीय मोहम्मद अली अराकी ईरान के सर्वोच्च धार्मि नेता बने।

१४ जून : अमरीका द्वारा फ्लोरिडा से २२ करोड़ डालर लागत से निर्मित 'टीटान-४' नामक राकेट प्रक्षेपित।

१५ जून : यूगोस्लाविया सरकार द्वारा परमाणु संयंत्र न ल की घोषणा।

विश्व-प्रसिद्ध श्रृंखला

विश्व-प्रसिद्ध खोजें
विश्व-प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्य
विश्व-प्रसिद्ध रोमांचक कारनामे
विश्व-प्रसिद्ध युद्ध
विश्व-प्रसिद्ध 101 व्यक्तित्व
विश्व-प्रसिद्ध धर्म मत एवं सम्प्रदाय
विश्व-प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी
विश्व-प्रसिद्ध रिकार्ड्स 1988-89
विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक
विश्व-प्रसिद्ध विनाश-लीलाएं
विश्व-प्रसिद्ध दुर्घटनाएं
विश्व-प्रसिद्ध गुप्तचर संस्थाएं
विश्व-प्रसिद्ध जासूस
विश्व-प्रसिद्ध प्रेरक प्रसंग
विश्व-प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियां
विश्व-प्रसिद्ध बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां
विश्व-प्रसिद्ध जासूसी कांड
विश्व-प्रसिद्ध क्रूर हत्यारे
विश्व-प्रसिद्ध सभ्यताएं
विश्व-प्रसिद्ध रोमांस कथाएं
विश्व-प्रसिद्ध अनमोल खजाने
विश्व-प्रसिद्ध दुस्साहसिक खोज-यात्राएं
भूत-प्रेत घटनाएं
जन-क्रांतियां
कुख्यात महिलाएं
नये प्रकाशन

- ■ विश्व-प्रसिद्ध भूत-प्रेत घटनाएं
- ■ विश्व-प्रसिद्ध जन-क्रांतियां
- ■ विश्व-प्रसिद्ध कुख्यात महिलाएं

मूल्य: 18/- प्रत्येक
डाकखर्च: 4/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें
मंगाने पर डाकखर्च माफ

■ प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री ■ प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित ■ सरस कथा शैली ■ फोटोटाइप सैट ■ बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई ■ बहुरंगी आवरण ■ वाजिब दाम

इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। उदाहरणार्थ ***रोमांचक कारनामे*** में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो **खोजें** में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। ***अनसुलझे रहस्य*** में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो ***खेल और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व*** व **वैज्ञानिक** जीवनी-प्रधान पुस्तकें हैं। ***विनाश-लीलाएं*** व ***दुर्घटनाएं*** में मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है तो ***गुप्तचर संस्थाएं, जासूस*** व ***जासूसी कांड*** में जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं। ***सभ्यताएं*** और ***प्रेरक-प्रसंग*** किसी भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो ***हत्यारे*** में रक्त पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। ***रोमांस-कथाएं*** में लैला-मजनूं से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं तो ***अनमोल खजाने*** में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं। ***दुस्साहसिक खोज-यात्राएं*** में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं तो ***जन-क्रांतियां*** में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का सिलसिलेवार ब्यौरा है। ***भूत-प्रेत घटनाएं*** पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी—कमजोर दिल के लोग इसे न पढ़ें तो अच्छा!

*कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने वाला एक सचित्र **मिनि एनसाइक्लोपीडिया** है।*

इस श्रृंखला में प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाड़ी 8. रिकार्ड्स-I 9. रिकार्ड्स-II 10. वैज्ञानिक 11. विनाश-लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा-पद्धतियां 17. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां 18. जासूसी-कांड 19. क्रूर हत्यारे 20. सभ्यताएं 21. रोमांस कथाएं 22. अनमोल खजाने 23. दुस्साहसिक खोज-यात्राएं 24. भूत-प्रेत घटनाएं 25. जन-क्रांतियां 26. कुख्यात महिलाएं।

तैयारी में/प्रेस में

★ राजनैतिक हत्याएं ★ तख्ता-पलट की घटनाएं ★ मांसाहारी व अन्य विचित्र पेड़-पौधे ★ हस्तियों के प्रेम-प्रसंग

English versions available

WORLD FAMOUS... 1. Discoveries 2. Unsolved Mysteries 3. Adventures 4. Wars & Battles 5. 101 Great Lives 6. Religions, Doctrines & Sects 7. Disasters 8. Accidents 9. Civilizations 10. Scientists 11. Spies 12. Intelligence Agencies 13. Spy Scandals 14. Brutal Murderers 15. Anecdotes 16. Love-Stories of the Great People.

अपने निकट व ए. एच. व्हीलर के रेलवे व बस अड्डों के बुकस्टॉलों पर मांगें। वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के पते :–

पुस्तक महल खारी बावली, दिल्ली-110006
शोरूम: 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.

ज्योति बसु का एकता नुस्खा

जनता दल के अध्यक्ष वीपी सिंह और जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के बीच एक युद्ध विराम हो गया है। इसे कराने में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की परोक्ष रूप से काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पिछले दिनों ज्योति बसु दिल्ली आये थे, तो उन्होंने चंद्रशेखर से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन उन दिनों चंद्रशेखर दिल्ली में नहीं थे। इसलिए मुलाकात नहीं हो पायी। ज्योति बसु ने चंद्रशेखर के निजी सचिव गौतम से कहा था कि वे मेरा एक व्यक्तिगत संदेश जब चंद्रशेखर दिल्ली लौटें, तो दें कि ज्योति बसु उनसे मिलने के बहुत इच्छुक हैं। इसके बाद चंद्रशेखर कालाहांडी के दौरे पर गये, तो उन्होंने कलकत्ता जाकर ज्योति बसु से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया। इसके पूर्व चंद्रशेखर बंबई गये हुए थे। वहां चंद्रास्वामी ने चंद्रशेखर से मुलाकात करके यह समझाने की कोशिश की कि उनको जनता दल में अपनी लड़ाई वीपी सिंह से और तेज करनी चाहिए। चंद्रशेखर ने चंद्रास्वामी की बात को सुन लिया था। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वीपी सिंह के खिलाफ उनको जनता दल में—व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि इस लड़ाई में वे जनता दल के अंदर अलग-थलग पड़ जायें। लेकिन चंद्रास्वामी ने इसी बात पर जोर दिया कि वे वीपी सिंह से अपनी लड़ाई और तेज करे, उसमें अंत में उनकी ही जीत होगी।

जब कलकत्ता में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात की, तो उनको बसु ने समझाया कि वीपी सिंह से झगड़ा करके वे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हिन्दी भाषी प्रदेशों में विपक्षी एकता को बहुत बड़ा धक्का भी लग सकता है। चंद्रशेखर ने बसु को अपनी निजी परेशानियां बतायीं जो वीपी सिंह उनके लिए पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्योति बसु ने उनको यही समझाया कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे उनके और वीपी सिंह के मतभेद बढ़ें। ज्योति बसु ने चंद्रशेखर को यह भी समझाया कि भारतीय जनंता पार्टी से चुनाव-तालमेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत न की जाये, अन्यथा नम्बूदिरीपाद उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे।

दूसरी तरफ, ज्योति बसु ने चंद्रशेखर से बात करने के बाद वीपी सिंह को भी अपने एक दूत के जरिये यह संदेश भिजवाया कि वे चंद्रशेखर से अपने मतभेदों को दूर करने के लिए पहल करें। चंद्रशेखर बिहार जनता दल के अध्यक्ष पद से अपने खास आदमी रघुनाथ झा के हटाये जाने से सख्त नाराज थे। वीपी सिंह ने झा को राष्ट्रीय स्तर पर किसी जगह 'एडजस्ट' कर देने का आश्वासन चंद्रशेखर को दे दिया है। दूसरी ओर, जनता दल के सांगठनिक विवादों को निपटाने के लिए बनी तदर्थ समिति के संयोजक आरिफ मोहम्मद खान चंद्रशेखर के साथ बहुत ही निकट का संबंध बनाये हुए हैं।

आरिफ की धमकी ?

क्या आरिफ मोहम्मद खान ने वीपी सिंह को जनता दल के महामंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी देकर पार्टी में संगठन के मामलों को हल करने के लिए बनी उच्च समिति के संयोजक का पद हथिया लिया ?

जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच तीव्र मतभेद, बिहार जनता दल के अध्यक्ष पद से रघुनाथ झा को हटाये जाने पर हो गये थे, उस समय आरिफ चंद्रशेखर की तरफ हो गये थे। वैसे भी आरिफ इलाहाबाद चुनाव के समय से वीपी सिंह से खिंचे-खिंचे रहते थे, क्योंकि उनको इस चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था। वीपी सिंह ने आरिफ की तुलना में उनके कट्टर विरोधी सैयद शहाबुद्दीन को इलाहाबाद चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया था।

चंद्रशेखर ने जब वीपी सिंह पर सीधा हमला करना शुरू किया, तो वे काफी परेशान हो उठे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने वीपी सिंह को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया कि वे चंद्रशेखर से अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद देवीलाल का झुकाव चंद्रशेखर की तरफ होने लगा था। वीपी सिंह इससे परेशान हो उठे, तो इसी बीच आरिफ ने दवाब डालने के लिए जनता दल के महामंत्री पद से अपना इस्तीफा वीपी सिंह को भिजवा दिया। इसके बाद वीपी सिंह ने आरिफ से बंद कमरे में बातचीत की। उसी बातचीत में आरिफ ने उनसे साफ कहा कि उनकी (वीपी सिंह) बजह से उनकी स्थिति जनता दल में बहुत खराब हो गयी है। वीपी सिंह ने इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि चूंकि चंद्रशेखर से आपके अच्छे संबंध हैं, इसलिए अब वे आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए नये सिरे से प्रयास करें। इसी बातचीत में यह सुझाव आया कि इस काम के लिए एक समिति बनायी जाये, जिसका संयोजक आरिफ को बनाया जाये। उसके बाद आरिफ और वीपी सिंह के सारे आपसी मतभेद दूर हो गये।

कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की खबर छप गयी कि आरिफ ने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आरिफ काफी परेशान हो गये। क्योंकि उस समय तक आरिफ वीपी सिंह के दाहिने हाथ के रूप में कार्य करने लगे थे।

गनी खां की परेशानी

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष गनी खां चौधरी कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी के इस फैसले से बहुत नाराज हैं कि कोई भी प्रदे कांग्रेसाध्यक्ष लोकसभा का चुना नहीं लड़ेगा। पता चला है कि ग खां ने राजीव गांधी से अनुरोध कि है कि उनको मालदा से लोकसभा चुनाव लड़ने की विशेष अनुमति जाये। लेकिन राजीव गांधी की तर से अभी तक उनको अनुमति न मिल पायी है।

पता चला है कि राजीव गां को इंका महामंत्री तथा प्रदे कांग्रेसाध्यक्षों को लोकसभा चुनाव लडाने का सुझाव गुलाम नबी आजा ने दिया था। गुलाब नबी यों कश्मीर के हैं, लेकिन पिछली बार महाराष्ट्र से चुनाव लड़ कर आये इस बार उनको कोई निर्वाचन क्षे नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पिछ दिनों उप्र में अपने लिए चुनाव क्षे की तलाश की थी। लेकिन बात बनी नहीं।

राजीव गांधी के इस फैसले इंका के तीन महामंत्री—केएन सिं गुलाब नबी आजाद तथा श्रीम शीला कौल प्रभावित हो रहे हैं। लोग लोकसभा के सदस्य हैं, लेकि अब चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। शी कौल की जगह तो शायद उनके गौतम कौल आईपीएस की नौकरी इस्तीफा देकर लड़ें या फिर उ दूसरे बेटे जो लंदन में हैं, आ चुनाव लड़ें। लेकिन केएन सिंह बहुत बडी समस्या हो रही है। बहुत परेशान हैं। तीन अ महामंत्री—आस्कर फर्नांडीज, वीए गाडगिल तथा एआर मल्लू हैं। इन मल्लू तो संसद सदस्य नहीं हैं। अ दोनों महामन्त्रियों के पास राज्यों चार्ज नहीं है। इसलिए चुनाव लड़ में कोई रोक नहीं है।

प्रदेश कांग्रेसाध्यक्षों में उप्र बलराम सिंह यादव, प० बंगाल गनी खां चौधरी, हिमाचल के सुल्तानपुरी, मप्र के चंदूलाल चंद्रा तथा कर्नाटक के वीरेंद्र पा लोकसभा के सदस्य हैं। ये लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सकता है कि वीरेंद्र पाटिल को का कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लिए तै करे। लेकिन गनी खां चौधरी ब ही उत्तेजित हैं। अगर राजीव ग गनी खां को चुनाव लड़ने की अनु दे देते हैं, तो केएन सिंह भी चु लड़ने की अनुमति मांगेंगे।

यह पन्ना तुलसी पॉकेट बुक्स की मिल्कियत है

एक खत का मजमून दिया जा रहा है। इस खत में एक पहेली छुपी है। मजमून को असावधानी से पढ़ने पर आपको लगेगा कि खत किसी कुबड़ा नामक व्यक्ति ने अपने हिंगले कार्बेट नामक दोस्त को लिखा है परन्तु खत को पढ़ते ही हिंगले बेहोश हो गया। क्या आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ? अगर आप मजमून को ध्यान से पढ़ें, जोड़-तोड़ करके पढ़ें तो जान सकते हैं। अतः पत्र को गौर से पढ़िये - एक बार समझ में न आये तो बार-बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिये कि इस खत को पढ़ते ही हिंगले कार्बेट कांपने क्यों लगा ? हमारा दावा है कि सवाल का जवाब खत के मजमून में ही छुपा है।

यह खत चोरी का है

प्यारे हिंगले कार्बेट,
आशा है कि पहले की तरह परेशान होगे
लेकिन अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है
और अब तो ये पांचो भी मेरे कब्जे में हैं
अब दुश्मन इनके जरिये नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा
तुम समझ सकते हो कि मैं शीघ्र ही तुम्हें
उसकी लाश दूंगा जो सोच रहा था कि 'तुम्हे
मारकर अपनी रियासत वापस ले लूंगा'
अब वह खुद हमारे जाल में फंस गया है।
तुम जानते हो कि ये पांचो चाहें तो तुम्हारी
संस्था में चार चांद लगा सकते हैं और दुश्मन की
रियासत को जलाकर खाक कर सकते हैं।
तुम्हारा शुभचिन्तक
कुबड़ा

इस खत में एक पहेली छुपी है

हमारा दावा है कि उपरोक्त पत्र को बार-बार पढ़ने के बावजूद आप नहीं समझ पाये हैं कि पत्र में ऐसा कहां, क्या लिखा है जिसे पढ़कर हिंगले आतंकित हो उठा। दरअसल उपरोक्त पत्र का मजमून वेद प्रकाश शर्मा के नये उपन्यास 'जुर्म की मां' से चुराकर इस पन्ने पर दिया गया है अतः अगर आप इस पत्र का रहस्य अथवा वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं तो 'तुलसी पॉकेट बुक्स' से प्रकाशित होने वाले वेद प्रकाश शर्मा के उस कथानक को पढ़ें जो 'जुर्म की मां' से शुरू होता है।

यह पन्ना वेद प्रकाश शर्मा के दिमाग की उपज है

गुप्तचर माहात्म्य

८ जून को दिल्ली दरबार के साउथ ब्लाक में जबरदस्त माथा-पच्ची हो रही थी। दरबार उप्र के दौरे से लौटे थे। आईबी (गुप्तचर एजेंसी) ने दरबार के दौरे का फीड बैक दिया था। उस फीड बैक में हर तरफ हरा-हरा ही था। दरबार के चुनावी दौरे का मूल्यांकन करनेवाली मल्टीनैशनल कंप्यूटरी टोली इस फीड बैक को लेकर असमंजस में पड़ी थी कि अगर दरबार के इमेज ग्राफ में आज इतनी बढ़ोतरी दिखा दी जायेगी, तो अगले कुछ महीनों में इमेज ग्राफ कंप्यूटर की स्क्रीन फाड़ कर बाहर निकल आयेगा। मामला आरके धवन के सामने पेश कर दिया गया। धवन ने रिपोर्ट देखी और हल्का-सा मुस्कराये। उन्होंने मन-ही-मन कहा, "१९७७ में हमारी दिवंगत मैडम (श्रीमती इंदिरा गांधी) के बारे में भी यह इसी तरह का सब्जबाग दिखा रही थी। लेकिन बाद में हर तरफ सूखा ही सूखा निकला।" धवन ने दरबार के चुनावी दौरे की फीड बैक रिपोर्ट को अपनी टेबुल पर रख लिया और कंप्यूटरी टोली को निर्देश दिया कि जनता दल में हो रही जूतीपैजार से कांग्रेस को कितना लाभ हो रहा है, इसकी एक हरी-हरी तस्वीर दरबार को दिखायी जाये, ताकि मनोबल ऊंचा बना रहे। उसके बाद आरके धवन ने रैक्स टेलीफोन पर आईबी चीफ से प्रेमालाप शुरू कर दिया।

धवन ने मन-ही-मन कहा, "१९७७ में हमारी दिवंगत मैडम के बारे में भी यह इसी तरह का सब्जबाग दिखा रही थी। लेकिन बाद में हर तरफ सूखा-ही-सूखा निकला।"

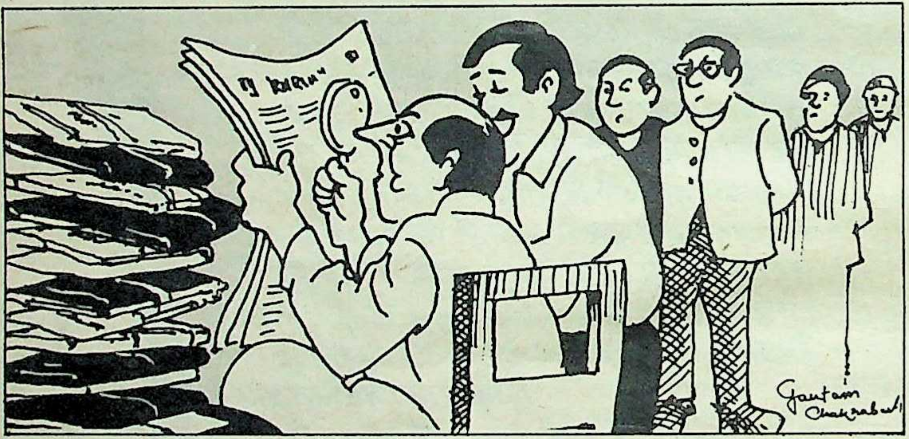

मेरे कंप्यूटरी एक्सपर्ट् कह रहे हैं कि विपक्ष से जो वोटर टूट रहा है, वह कांग्रेस में पूरा-का-पूरा न आकर, उसका एक बड़ा हिस् 'कोप-भवन' में जा रहा है।

दरबार को कारिंदे जनता दल में चल रही मुक्केबाजी पर अपनी ताजा रिपोर्ट दिखाकर राजा मांडा और बलिया नरेश चंद्रशेखर के मल्लयुद्ध की वीडियो फिल्म दिखाने को हुए, तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना को छिपाने के लिए आंखों पर काला चश्मा लगाये नयी दिल्ली तिवारी (नारायण दत्त तिवारी) ने हाथ जोड़ कर कक्ष में प्रवेश किया, "सर, आप जो पंचायतों के फिर से चुनाव करवा कर महिलाओं तथा हरिजनों आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने के छक्के-अट्ठे पिछले दिनों यूपी में मार कर आये, वे जानलेवा बन गये।" दरबार ने तपाक से कहा, "हां, हां...। आप पंचायतों के फिर से चुनाव करायें और उनमें महिलाओं को ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दें। लड़के (१८ की आयुवाले) तथा महिलाएं हमारा नया वोट बैंक हैं।" तिवारीजी हाथ जोड़े-जोड़े बैठ गये, आप जैसा कहेंगे, वैसा ही होगा। लेकिन...।" तिवारीजी का 'लेकिन' दरबार को नहीं भाया, "चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है और आप लेकिन...किंतु और परंतु की रट में पड़े हुए हैं। देखिए तिवारीजी, मैंने 'अब देखना है...हमको सोचना है', आदि अनादि छोड़कर 'हम कर रहे हैं...हम करेंगे' कहनां शुरू कर दिया है, तो आपको भी लेकिन...किंतु और परंतु छोड़कर मेरे स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। अब तो वीरू उस्ताद का भी डर आपको नहीं है।" तिवारीजी हाथ जोड़े-जाड़े उठ खड़े हुए, "सर, एडवांस में क्षमा मांग कर मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे लिए तो जो आपने कहा, वही कानून है। लेकिन शासन तंत्र कानून के जरिए ही चलता है। अभी पंचायती कानून नहीं बना है। ऐसी स्थिति में...।" दरबार ने अपना मुंह गोल कर लिया, "ओ आई सी...। मैं समझा। ठीक है...ठीक है। अगले मानसून सत्र में हम पंचायती राज को कानूनी पायजामा पहना देंगे।" दरबार ने उसके बाद पास खड़े जी पार्थसारथी की तरफ प्रश्नचिह्न की मुद्रा में देखा। पार्थसारथी सकपका गये, "सर, मैंने आपके भाषण में सब कुछ ठीक-ठाक ही लिखा था। हो सकता है कि उसके हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो गयी हो।" पीछे खड़ा हिंदी अनुवादक बुदबुदाया, "अनुवाद की कोई गलती नहीं है। सरकार जब नोट्स से अलग हटकर एक्सटेम्पोर बोलने लगते हैं, तो यह सब गुड़-गोबर हो जाता है।"

धवन ने दरबार के
नावी दौरे की फीड
क रिपोर्ट को अपनी
बुल पर रख लिया
और कंप्यूटरी टोली
को निर्देश दिया कि
ंनता दल में हो रही
ूतीपैजार से कांग्रेस
ो कितना लाभ हो
रहा है, इसकी एक
हरी-हरी तस्वीर
रबार को दिखायी
ाये, ताकि मनोबल
ऊंचा बना रहे।

पार्थसारथी ने अनुवादक के बुदबुदाते मुंह पर हाथ रख दिया, "अब दरबार ने कुछ बोलना (एक्सटेम्पोर) शुरू किया है, तो तू उस पर नजर लगा रहा है। अनुवाद की फाइल मेज पर रखकर यहां से चल फूट ले।" अनुवादक गुस्से में आकर फाइल मेज पर पटक बुदबुदाता हुआ कक्ष से निकलने लगा, तो तिवारीजी नें अपना काला चश्मा उतार उस अनुवादक के भाग्य को सराहा, "हे अनुवादक, तू कितना सुखी है। कम-से-कम बुदबुदा तो लेता है।" इसी बीच आईबी चीफ के साथ आरके धवन कक्ष में आ चुके थे। चीफ अपनी बात शुरू करें कि उसके पहले धवन ने तिवारीजी को इशारा किया कि वे काला चश्मा पहन लें, उनकी नंगी आंखें अपनी कलाकारी दिखा रही हैं।" तिवारीजी ने तुरंत अपना काला चश्मा लगा लिया, लेकिन वे कुछ नर्वस' हो गये थे। इसलिए कक्ष के बाहर चले गये। कक्ष के बाहर जाते ही जैसे ही चीफ बोलने को हुए, धवन ने बात काट दी, "सर, वीरू उस्ताद के न रहने से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति तुरंत की जानी जरूरी हो गयी है।" दिल्ली दरबार ने सोचने के लिए अपनी त्योरी चढाई, तो धवन करीब आकर कान में फुसफुसाये, "सर, राजनीति यही कहती है कि किसी भी सूबेदार (मुख्यमंत्री) को चैन से बैठने दिया गया, तो उसकी निगाह दिल्ली दरबार पर आकर टिक जाती है। तिवारीजी अपनी निगाह को ढकने के लिए काला चश्मा पहनने लगे हैं। समय रहते हम लोगों को पेशबंदी कर लेनी चाहिए। पिछले दिनों तीन दिन तक लल्लू (लोकपति त्रिपाठी) दरबार की चौखट पर पड़े रहे। वीरू उस्ताद का विकल्प बनने का प्रार्थना पत्र दे गये हैं। सर, आपकी मेज पर पूरी फाइल तैयार करके मैंने रख दी है। उसमें और भी बलराम सिंह यादव आदि अनादि के 'एप्लीकेशन' हैं। आप विचार करके इस संबंध में कोई फैसला जल्दी कर लें।" दरबार ने अपनी मुड़िया हिला दी, तो आईबी चीफ दरबार से मुखातिब हो गये, "सर, आपके पास जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं, उनको चैक और काउंटर चैक करके ही भेजा जा रहा है। शक-संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।" दरबार ने पूछा, "अरे भाई, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता दल में जो उठा-पटक चल रही है, उससे वोटर विपक्ष से कट कर कांग्रेस के पक्ष में आने चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि वे हमारे पक्ष में तेजी से टूट रहे हैं। लेकिन मेरे कंप्यूटरी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि विपक्ष से जो वोटर टूट रहा है, वह कांग्रेस में पूरा-का-पूरा न आकर, उसका एक बड़ा हिस्सा 'कोप भवन' में जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह वोटर 'बफर' क्यों बनाता जा रहा है। उसे खुलकर मेरे पक्ष में आना चाहिए।" चीफ ने कहा, "सर, हमारा फीडबैक तो यही बता रहा है कि वोट का कोई 'बफर' नहीं बन रहा है। विपक्ष से निराश होकर वोटर आपकी शरण में आ रहा है। इसीलिए आपका इमेज ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है।" दिल्ली दरबार इमेज ग्राफ से ऊपर जाने की बात सुनकर गद्गद हो उठे और अपनी छाती में हवा भरते हुए कहा, "मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा इमेज ग्राफ काफी ऊंचा जा रहा है। चूंकि मैंने २१वीं शताब्दी में मुल्क को ले जाने की बात को छोड़कर पंचायती युग में उसे ले जाने का बीड़ा उठा लिया है, इसलिए मुझे इन कंप्यूटरों के चक्करों से भी मुक्त होना चाहिए।"

चीफ के जाते ही दरबार ने आदेश दिया कि "गुप्तचर रिपोर्ट को ही कंप्यूटर में फीड किया जाये।" धवन ने कुछ कहने के लिए गला खंखारा, तो दरबार ने उनको टोक दिया, "देखिए धवनजी, हमारे पास समय की बहुत कमी है।" धवन ने अदब से दोहरे होकर कहा, ओके सर, आप जैसा कहें।" वे कक्ष से बाहर आ गये। धवन के कक्ष से बाहर आते ही गुप्तचर मुख्यालय से रैक्स पर दरबार को बताया गया कि कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के प्रधान भरत महाराज का निधन हो गया। दरबार ने पूछा कि 'यह महाराज कौन हैं?" फिर उनको याद आ गया कि मैडम गांधी उनको बहुत मानती थीं। दरबार ने आदेश दिया कि भरत महाराज के निधन पर उनका एक शोक संदेश तुरंत जारी किया जाये। कारिंदे हरकत में आ गये।

दरबार की तरफ से एक शोक संदेश तैयार करके कलकत्ता के समाचार पत्रों को प्रोफेसर केके तिवारी के पत्र सूचना कार्यालय से जारी किया गया। जब भरत महाराज के निधन पर दिल्ली दरबार का शोक संदेश कलकत्ता के समाचार पत्रों के मुख्यालय में पहुंचा, तो संपादकों ने शीर्षासन करना शुरू कर दिया। भरत महाराज अभी पूरी तरह जीवित थे। दिल्ली दरबार ने उनको क्यों मार दिया? संपादकगण जब शीर्षासन से अपने पैरों पर आये, तो उन्होंने अपने दिल्ली स्थित संवाददाताओं की खाट खड़ी कर दी। संवाददाताओं ने जब दरबार के कारिंदों को बताया, तो उनका छोटा सा उत्तर था, "अगर भरत महाराज नहीं मरे हैं, तो शोक संदेश मत छापो।"

आठ जून की ही रात को सारा मामला धवन के सामने पेश कर दिया गया। धवन ने उसे बहुत गंभीरता से लिया। जब मामला घूम फिर कर यह आया कि आईबी ने दिल्ली दरबार के चुनावी दौरे पर अपनी जो रिपोर्ट दी है, क्या उसको भी गंभीरता से लिया जाये? मय धवन के सब चुप हो गये—दुल्हन वो जो पिया मन भाये।

—दरबारी लाल

मुझे भी ऐसा
लगता है कि मेरा
इमेजग्राफ काफी
ऊंचा जा रहा है।
चूंकि मैंने २१वीं
शताब्दी में मुल्क को
ले जाने की बात
को छोड़कर पंचायती
युग में उसे ले जाने
का बीड़ा उठा लिया
है, इसलिए मुझे इन
कंप्यूटरों के चक्करों
से भी मुक्त होना
चाहिए।

साढ़े चार वर्ष में डेढ़ सौ नये कानून

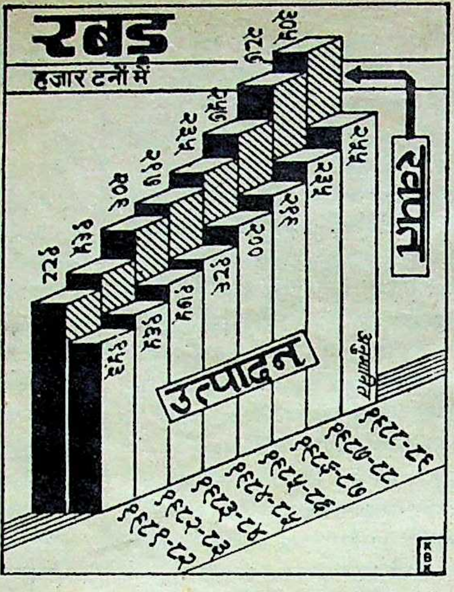

राजीव सरकार ने अपने शासनकाल के साढ़े चार वर्षों में डेढ़ सौ नये कानून बनाये और करीब इतनी ही संख्या में पुराने कानूनों में संशोधन किये। राजीव सरकार ने इस अवधि में संविधान में १२ संशोधन किये।

भारत २२ मई को जमीन से जमीन पर प्रहार करनेवाले 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण कर ऐसे प्रक्षेपास्त्र रखनेवाला विश्व का पांचवा देश हो गया है। ऐसे प्रक्षेपास्त्र फिलहाल रूस, अमरीका, चीन और फ्रांस के पास हैं।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र सात किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अंतरिक्ष में ३६० किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाता है और कंप्यूटर संचालित होकर अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए वह ढाई किलोमीटर प्रतिसेकेंड की गति से पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह प्रक्षेपास्त्र अधिकतम २५०० किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इस प्रक्षेपास्त्र के जरिए परमाणु बम का भी प्रहार किया जा सकता है।

अग्नि प्रक्षेपास्त्र के पहले भारत के वैज्ञानिकों ने २९ अप्रैल, १९८७ को ९ किलोमीटर तक मार करनेवाले 'त्रिशूल' प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद बना २९ किलोमीटर तक मार कर सकनेवाला प्रक्षेपास्त्र 'आकाश'। २५ फरवरी, १९८८ को श्रीहरिकोटा से 'पृथ्वी' नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था। यह प्रक्षेपास्त्र तो एक हजार किलोमीटर से भी अधिक दूर तक पहुंचा था।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत सरकार पर जून, १९८४ के आपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए एक हजार करोड़ रुपए का दावा दायर किया हुआ है। कमेटी ने यह दावा अमृतसर में किया था, जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दिल्ली उच्चन्यायालय में लाया गया था। सरकारी पक्ष का कहना है कि आपरेशन ब्ल्यू स्टार संप्रभु शक्तियों के तहत सरकार की कार्यवाही थी, अतः सरकार पर किसी हरजाने का दावा नहीं किया जा सकता, जबकि कमेटी के वकील की दलील थी कि १९८४-८५ के चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल ने आपरेशन ब्ल्यू स्टार का जमकर विद्वेषपूर्ण प्रचार किया था। अतः इसे सरकार की कार्यवाही कहना तर्कसंगत नहीं। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादीवाला यदि कोई देश है, तो वह भारत है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल कानून को संहिताबद्ध करनेवाला पहला देश भी भारत ही है। दो वर्ष पहले इस्लाम के प्रख्यात विद्वान मुफ्ती फसील-उल-रहमान हिला उस्मानी ने यह काम शुरू किया था और इसे गत अप्रैल में पूरा कर लिया है।

ब्रिटेन ने दिल के दौरे की एक अचूक दवा खोज निकाली है। इमिनसे नामक इस दवा का एक इंजेक्शन हृदयाघात के मरीज को ठीक करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह दवा इतनी महंगी है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा के एक इंजेक्शन की कीमत ५०० पौंड (करीब साढ़े तेरह हजार रुपए) है।

भारत के नोबल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री और अंतरिक्षविद ७९ वर्षीय डा० चंद्रशेखर ने यह दलील देते हुए अपने ऊपर बननेवाली फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया कि मेरी न तो इसमें दिलचस्पी है और न ही मेरे पास समय है। डा० चंद्रशेखर फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय की खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं।

पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पाक मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद खान जुनेजो ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु नामजद पाकिस्तानी उम्मीदवार के पक्ष में भारत का समर्थन हासिल करने के लिए भारत सरकार को पाक से संबंधित कुछ अतिमहत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं दी थीं, फिर भी भारत ने पाक प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया।

देश में एक जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस देने की नयी नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत अब लर्नर लाइसेंस ट्रैफिक के निशानों और नियमों की जानकारी की परीक्षा पास करने पर ही मिल सकेगा। साथ ही आवेदकों को मैडिकल टेस्ट में भी पास होना होगा। परिवहन गाड़ी चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उक्त दो परीक्षाओं के साथ ही ड्राइविंग स्कूल से निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ये प्रावधान नये मोटर गाड़ी अधिनियम में सन्निहित हैं, जिसके लागू होने से ५० बरस पुराना मोटरगाड़ी अधिनियम खुद ही रद्द हो जायेगा।

सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का मासिक वेतन १२ रूबल (करीब ३०,००० रुपए) पोलितब्यूरो के हर सदस्य को वेतन मिलता है। गोर्बाचेव अनुसार रूस के आम श्रमिक मिलनेवाले वेतन का यह पांच गु है। गोर्बाचेव को पुस्तकों के लेखन जो आमदनी होती है, वह पार्टी में चली जाती है।

देश के २१ राज्य परिवहन नि पिछले दो सालों में ९७३ करोड़ का घाटा दे चुके हैं। देश भर राष्ट्रीयकृत सड़कों पर इन निग की करीब एक लाख बसें चलती जिनके लिए ७ लाख कर्मचारी तैन हैं। सभी निगम किराये के रूप प्राप्त एक रुपए में से औसतन ३३ स्टाफ पर, ३३ पैसे ईंधन लुब्रिकेटिंग पर और १२ पैसे टै पर खर्च करते हैं, लेकिन रोचक त यह है कि भिन्न-भिन्न राज्यों निगम के कर्मचारियों के वेतनमा में बहुत फर्क है। गुजरात परिव निगम के हर कर्मचारियों को सर्व धिक रोजाना औसतन ५६.८४ प्रति किलोमीटर मजदूरी मिलती जबकि मध्य प्रदेश के निग कर्मचारियों को न्यूनतम औसत ३०.१८ पैसे ही प्रतिदिन मिलते

उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्याल (रुहेलखंड विवि) ऐसा भी है, जि दिवालिया होने से बचने के लिए बैं को अपना प्रशासनिक भवन ४ लाख रुपए में गिरवी रखना पड़ा

संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व खा परिषद के अनुसार दुनिया की कु ५.२ अरब आबादी में से ५५ करो लोग ऐसे हैं, जिन्हें दो वक्त भरपेट भोजन नसीब नहीं हो पात अर्थात दुनिया में हर दस लोगों में एक व्यक्ति को भूखों ही सोना पड़ है।

अमरीका में पहली बार यह कानू बना है, जिसके अनुसार प्रेमी-युग को साथ रहने के लिए अब विवा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ब अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होग रोमन कैथोलिकों के घोर विरोध बावजूद यह कानून बनाया गया

—संयोजन : विनोद मि

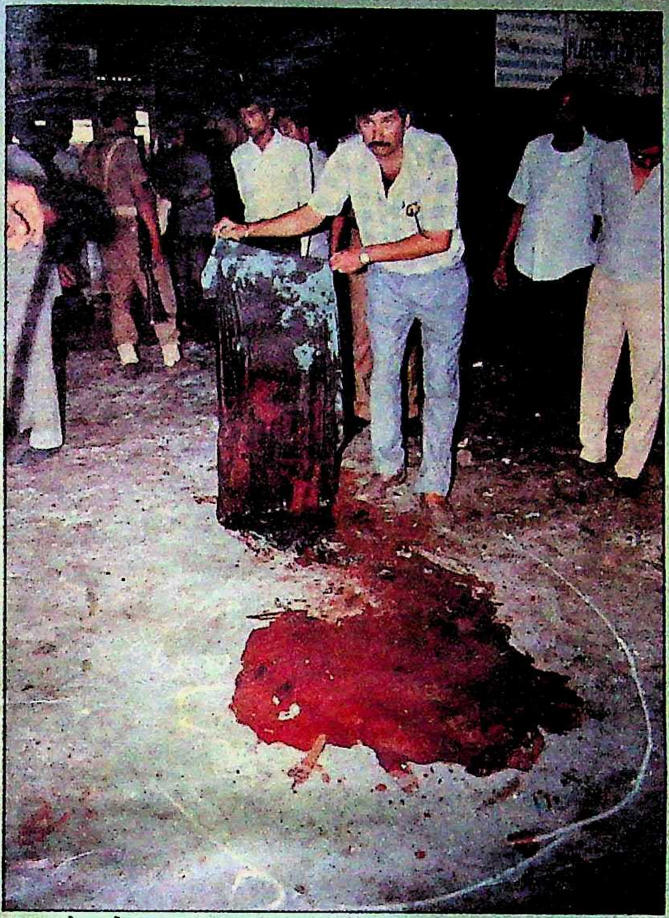

छाया : अशोक वाही

बम विस्फोट

आशंका सभी को थी कि पस्तहिम्मत हो चुके आतंकवादी ४ जून से ११ जून के बीच देश में कहीं भी, खासकर पंजाब और दिल्ली में कोई बड़ा नरसंहार कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों १९८४ में स्वर्ण मंदिर में हुए आपरेशन ब्ल्यू स्टार की याद में 'घल्लूघारा सप्ताह' मनाते हुए आतंकवादी हर वर्ष नरसंहार करते रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में पुलिस ने दिल्ली में 'रेड अलर्ट' की भी घोषणा कर रखी थी। बहरहाल, ११ जून तक तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन १२ जून को दिल्ली में सुबह दस बजकर, ३५ मिनट पर नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए एक भयानक बम-विस्फोट ने आठ यात्रियों के चियड़े उड़ा दिये तथा ५३ यात्रियों को बुरी तरह घायल कर दिया। इस बम में ट्राईनाइट्रो टाल्वाइन (टीएनटी) रसायन और डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ यात्रियों के चियड़े २५ फुट ऊंची छत से जा टकराये और फर्श पर एक फुट गहरा गड्ढा हो गया। बम-विस्फोट के बाद का हृदय-विदारक माहौल :

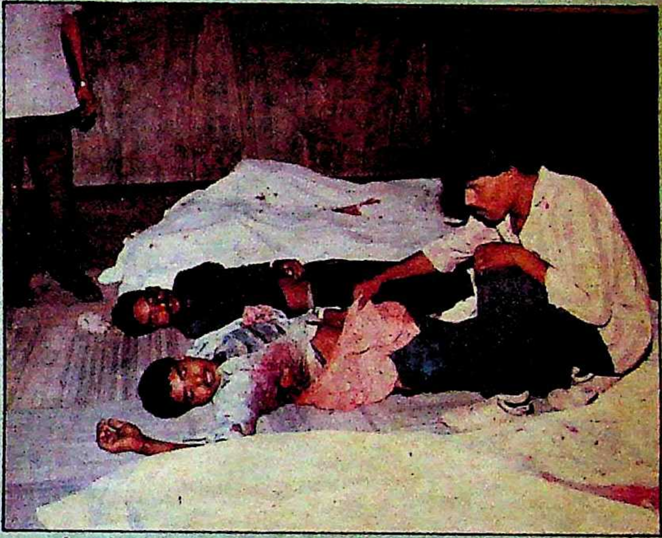

छाया : सुनील सक्सेना

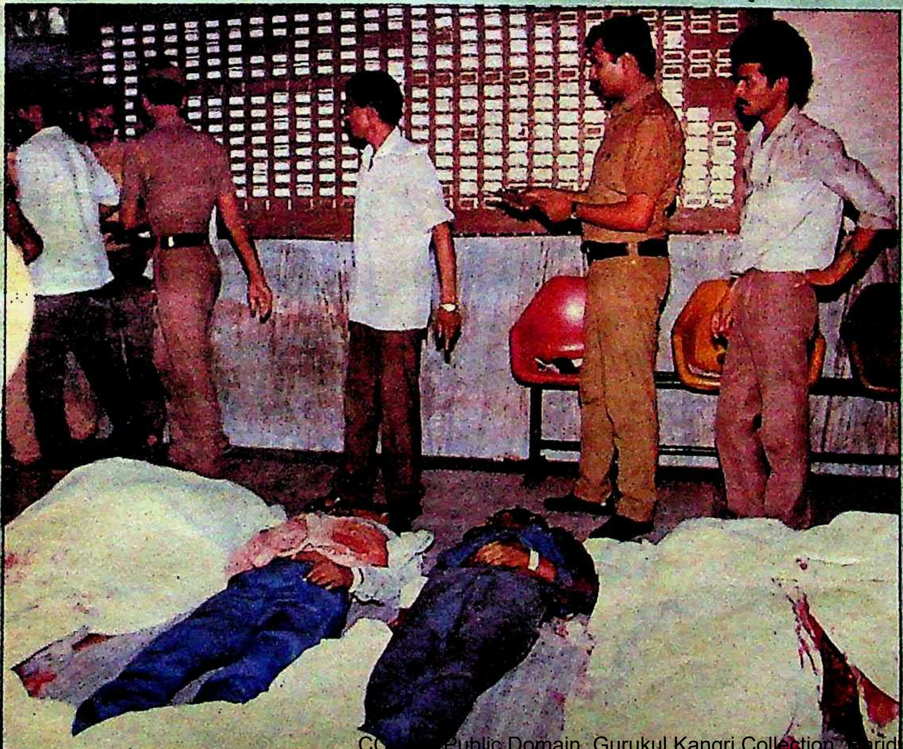

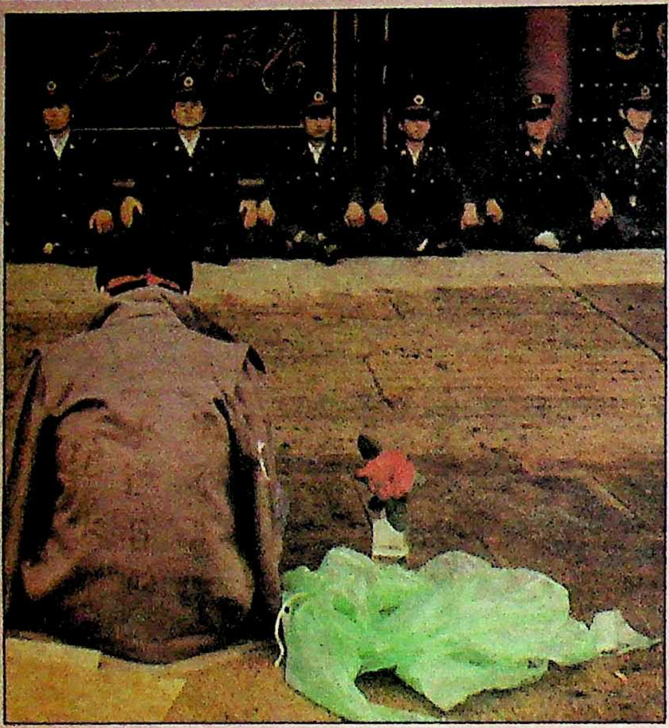

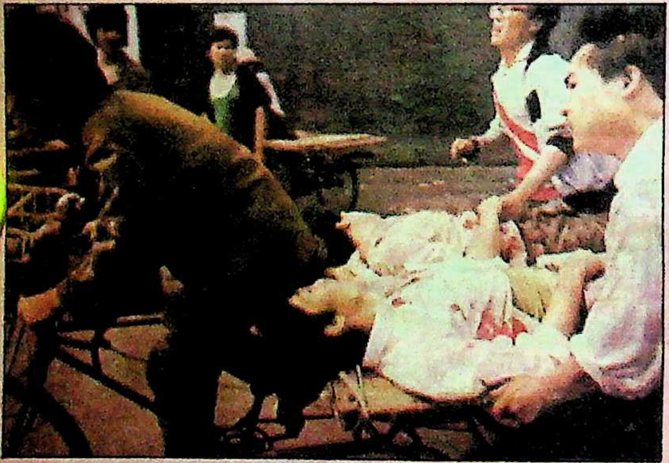

चीन में दमन

चालीस साल पहले माओत्से तुंग के नेतृत्व में जब कम्युनिस्टों ने च्यांग काई शेक की सरकार को उखाड़ फेंका था, तब उनका प्रमुख नारा 'रोटी' ही था, लेकिन गत १५ अप्रैल को कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व महासचिव सुधारवादी हू याओ पंग के निधन पर पेइचिंग के ग्रेट हाल आफ पीपुल के सामने थ्येनआनमन चौक में आयोजित चीनी युवकों की शोक सभा भ्रष्ट नेताओं को हटाने और लोकतंत्र की मांग करनेवाले सत्याग्रह में बदल गयी। 'रोटी हमें प्रिय है, लेकिन लोकतंत्र हमें रोटी से भी अधिक प्यारा है' के नारे लगाते चीनी युवकों ने अमरीका की 'आजादी की देवी' की प्रतिमा की तर्ज पर वहां लोकतंत्र की देवी की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी थी । चीनी सेना ने ३ जून तक सत्याग्रहियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की (ऊपर बायें), लेकिन अचानक ४ जून को चीनी सेना ने टैंकों और राइफलों से हमला करके थ्येनआनमन चौक खाली करवा

BJP
DEMOCRACY

छाया : सुनील सक्सेना

लिया। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हुए चीनी छात्र (ऊपर) ! इस नरसंहार के विरोध में अनेक देशों में युवकों और राजनीतिक संगठनों ने सभाएं व प्रदर्शन किये। दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन करते हुए (ऊपर इनसेट)।

मादक पदार्थों की होली

दुनिया के अनेक मुल्कों ने नशीले पदार्थों को राष्ट्रघाती मानकर इनके सौदागरों के लिए सजा-ए-मौत की व्यवस्था की है। लेकिन भारत में ऐसे अपराधियों के लिए मौत की सजा का कोई विधान नहीं है, बहरहाल, गत ९ जून को दिल्ली पुलिस ने पिछले दस वर्षों में पहली बार ७०० ग्राम हशीश, एक किलो हेरोइन, ७१ किलो गांजा, ८० किलो अफीम के डोडे तथा ६० किलो भांग सहित दस करोड़ रुपए मूल्य की करीब एक हजार किलोग्राम मादक सामग्री को दिल्ली में यमुना तट पर आग के हवाले कर दिया। अनुमान है कि अभी दिल्ली पुलिस के मालखाने में २४ हजार किलो मादक पदार्थ पड़ा है। पुलिस आयुक्त विजय करण मादक पदार्थों की होली जलाते हुए (नीचे)।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

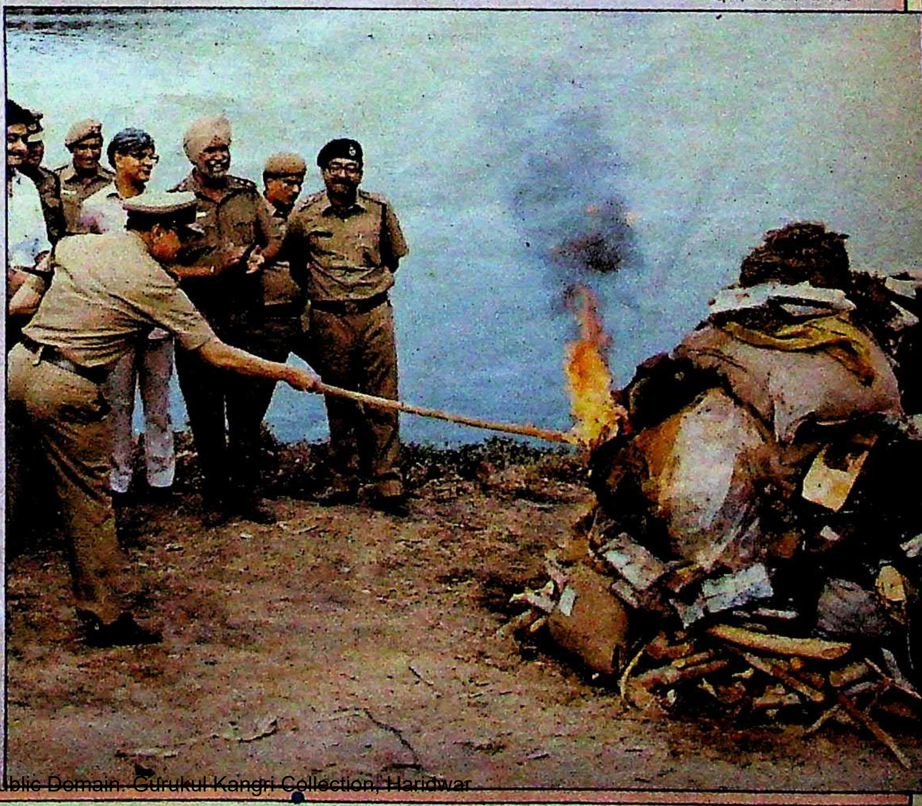

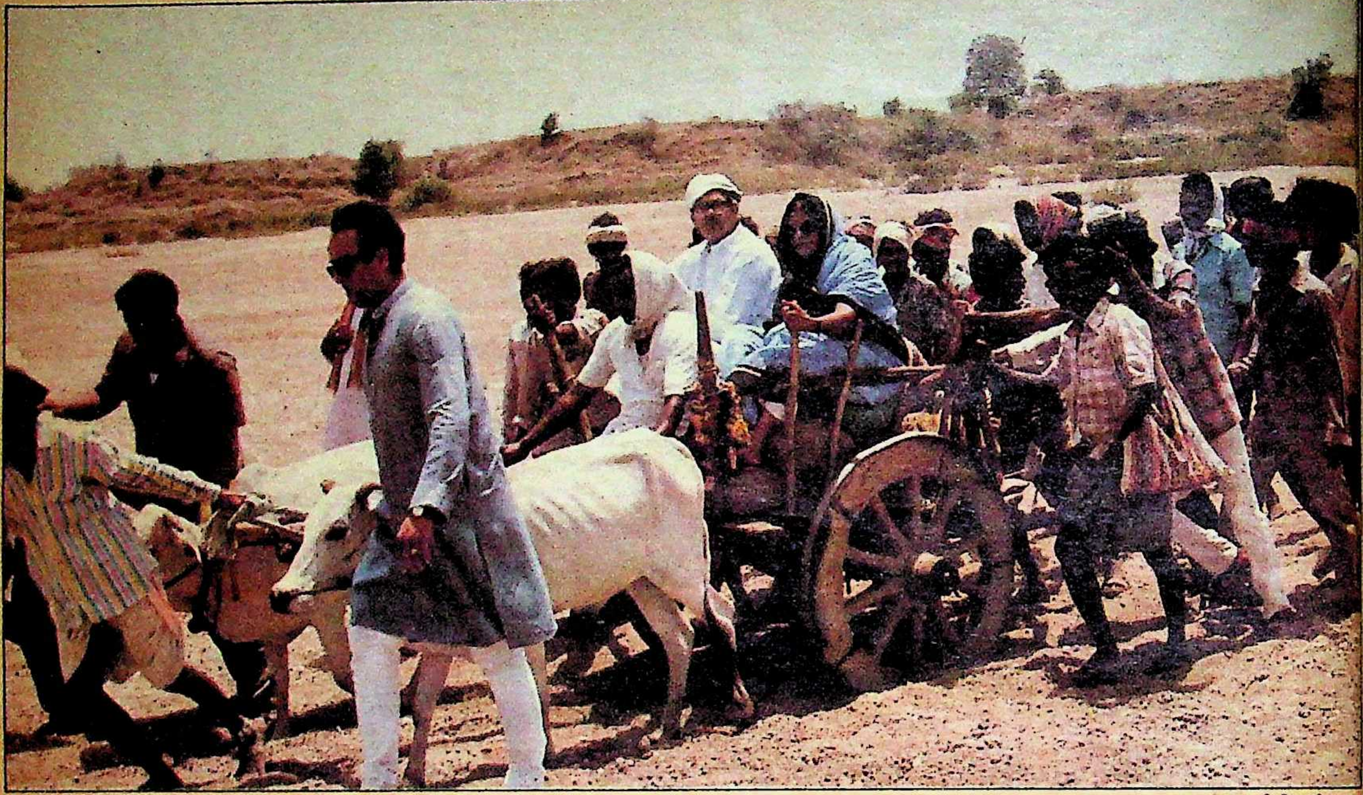

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

विश्वनाथ प्रताप सिंह

महाराष्ट्र सरकार आदिवासियों से तेंदू पत्ते के जिन सौ पुड़ों को २० रुपए में खरीदती है, उन्हें आंध्र प्रदेश न केवल ३० रुपए में खरीदता है, बल्कि इसके अलावा उन्हें २ किलो चावल, एक रुपए की इमली तथा दो रुपए का तेल भी देता है। महाराष्ट्र के आदिवासियों के साथ हो रहे इस पक्षपात का विरोध करने के लिए खुद वीपी सिंह ने महाराष्ट्र से तेंदू पत्ता ले जाकर आंध्र प्रदेश में बेचा। वीपी सिंह, मृणाल गोरे (बैलगाड़ी पर), संजय सिंह (बैलों के पास) तेंदू पत्तों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अलापल्ली कस्बे से आंध्र प्रदेश के बेगमपल्ली गांव की ओर जाते हुए (ऊपर)।

अल्पायु में अचानक दिवंगत वीर बहादुर सिंह की तेरहवीं के दिन उनकी मां श्रीमती ऊदा को सांत्वना देते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह (दायें)!

छाया : मनमोहन शर्मा

कैप्टन शामजी : कच्छ का भेदिया या शुभचिंतक ?

इस समय गुजरात पुलिस के लिए एक व्यक्ति जटिल पहेली बना हुआ है। वह व्यक्ति है शामजी वीरजी छेड़ा। पुलिस उसे शातिर जासूस मानकर चल रही है, लेकिन अभी वह इस बात के पक्के प्रमाण जुटा पाने में असफल है। दूसरी ओर कच्छ के लोग उसे अपना हमदर्द मानते हैं। शामजी इस समय गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। प्रस्तुत है, इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में 'माया' की छानबीन :

मीठी-मीठी बातों से रिझाने और किसी भी विषय पर विशेषज्ञ की तरह बातें करके प्रभावित करने में उसका कोई जवाब नहीं। उसमें एक ओर सरकार के प्रति घृणा का भाव हैं, तो दूसरी ओर कच्छ क्षेत्र के प्रति बेइंतहा प्यार। उसने पाक सीमा से लगे सामरिक महत्व के भारतीय क्षेत्र में एक द्वीपनुमा स्वतंत्र देश का खाका बनाया है। लेकिन फिलहाल वह सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन के आरोप से छूटने की प्रतीक्षा में गुजरात के एक जेल में पड़ा सड़ रहा है।

वह व्यक्ति है कैप्टन शामजी वीरजी छेड़ा, जिसके बारे में पक्का संदेह है कि वह बहुत बड़ा जासूस है, लेकिन जिसके खिलाफ केस बहुत ही कमजोर है। सच कहा जाये, तो यह आदमी अभी भी पुलिस, राजनेताओं और लोगों के लिए एक गूढ़ पहेली बना हुआ है और उसके बारे में उनकी परस्पर विपरीत और भिन्न राय है। कई उसे बहुत ही खतरनाक मानते हैं, तो कई सिर्फ खप्ती मानते हैं।

वंश परंपरा से कच्छी शामजी बंबई में पैदा आ। पिता धनी था, इसलिए उसे कपड़े के निर्यात-ापार में लगा दिया। शामजी मैट्रिक भी नहीं है, किन वह कमर्शियल पाइलट का लाइसेंस पा गया । ५० के ऊपर हो चुका शामजी अमरीकी लहजे में र्राटेदार अंगरेजी बोलता है।

कच्छ के आसपास शामजी को पहली बार ९८०-८१ में देखा गया। वह पूरे साल भर दरगाह के शहर कांडला में एक होटल के कमरे आराम करता रहा और कभी-कभार सैनिक ष्टि से संवेदनशील इलाकों के चक्कर भी लगा ाता था। वैसे यह बात महत्वपूर्ण है कि उसके पूर्वज च्छ जिले के अबदासा तालुका के एक गांव के थे, किन अब उस गांव में इन लोगों की न जमीन है, न ोई रिश्तेदार रहता है, ऐसे में इतने समय तक सके वहां रुकने का कोई कारण नहीं था।

संदिग्ध गतिविधियां : साल भर रहने के बाद ह उस सीमावर्ती इलाके से गायब हुआ और बंबई गया। १९८३ में वह फिर कच्छ पहुंचा और इस इलाके के विकास की बड़ी-बड़ी बातें करने लगा। उसने अपना दफ्तर खोला और कच्छ को अहमदाबाद और बंबई से जोड़ने वाली निजी विमान सेवा शुरू करने की बात शुरू की। प्रेस कांफ्रेंस हुई और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया। फिर उसने शहर के जाने-माने लोगों के साथ कच्छ की उपेक्षा की बात शुरू की और वह समझ गया कि उसने लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वह लोगों में संकीर्णता भरने के लिए तर्क दिया करता था कि जैसे यहूदियों के लिए इस्रायल है, इसी तरह कच्छियों के लिए कच्छ होना चाहिए।

उसे शायद पता नहीं था कि अब तक वह राज्य की खुफिया पुलिस की नजर पर चढ़ चुका था। अब उसने अपना डेरा पाकिस्तान सीमा से लगे दिनारा गांव में डाला और यहां वह गांधी सेवा आश्रम में छह महीने तक रहा। इस दौरान वह सीमा से लगे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों और सैनिक ठिकानों को देखने जाता रहा। बीच-बीच में वह विमान से उड़कर बंबई आता था और हर बार एक नयी औरत के साथ लौटता था।

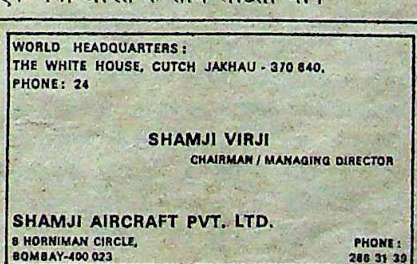

WORLD HEADQUARTERS :
THE WHITE HOUSE, CUTCH JAKHAU - 370 640.
PHONE : 24

SHAMJI VIRJI
CHAIRMAN / MANAGING DIRECTOR

SHAMJI AIRCRAFT PVT. LTD.
8 HORNIMAN CIRCLE,
BOMBAY-400 023
PHONE :
286 31 39

जिस तरह से शामजी नयी कंपनी खोलने की कागजी घोषणा कर देता था, वह भी चक्कर में डालने वाला है। कहते हैं कि उसने ऐसी करीब दर्जन भर कंपनियों की घोषणा की। उसके विजिटिंग कार्ड में उसे शामजी एअरक्राफ्ट्स का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बताया गया है।

खुफिया विभाग के अनुसार उसकी गतिविधियां संदेहास्पद थीं और जब यह खबर मिली कि वह बाहर भाग सकता है, भुज नगर की पुलिस ने उसे ५ अगस्त, १९८३ को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के समय वायु सेना के एक अधिकारी की पूर्व पत्नी प्रमिला पांगड़े उसके साथ थी। वकालत की शिक्षा प्राप्त कोल्हापुर की प्रमिला कुछ समय से उसके साथ रह रही थी। शामजी ने पुलिस को बताया कि प्रमिला उसकी पत्नी है। बाद की जांच में पता चला कि प्रमिला की एक सात साल की बेटी भी है।

जांच से यह भी पता चला कि शामजी की पहले विमला बेन से शादी हुई थी और इन दोनों के तीन बच्चे भी थे, जिनमें बेटा संजय तो २८ वर्ष का है। शामजी की हरकतों से तंग आकर विमला बेन ने उसे छोड़ दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि शामजी ने अमरीका में भी एक शादी कर ली थी, जिससे नाराज होकर ही विमला बेन उससे अलग हुई।

जखाऊ में अड्डा : गिरफ्तारी के समय उसके पास से ढेर सारे कागजात, एक पाइलटवाला बैज और नक्शा बनानेवाले उपकरण बरामद हुए। उसे फौजदारी कानून की धारा ४१ (१) और ४०२ के तहत गिरफ्तार किया गया था। पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं इस मामले की विस्तृत जांच की और उसे छोड़ दिया। शामजी ने तुरंत कच्छ छोड़ दिया। इस दौरान यह भी देखा गया कि उसे सेना के लोगों से मेलमिलाप का शौक था।

लेकिन मामला यहीं खतम नहीं हुआ। १९८७ में वह फिर कच्छ लौटा और उसने पुराने उत्साह से अपना काम शुरू किया। इस बार उसने नालिया तालुका के जखाऊ गांव में अपना डेरा डाला। यह गांव एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और उस समय मछली मारने और तस्करी का केंद्र भी था। कराची के करीब होने के कारण जखाऊ को कच्छ और मध्य पूर्व का द्वार कहा जाता है। नालिया तालुका में भी प्रतिरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं।

कच्छ के विकास की बात का प्रचार उसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया। 'कच्छ जागें' नामक स्थानीय अखबार को दी गयी भेंटवार्ता में उसने जखाऊ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाने का वादा किया था। औद्योगिक परिसर बनाने, फ्लाइंग क्लब, भुज को अहमदाबाद और बंबई से जोड़ने वाली निजी विमान सेवा तथा अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का खूब प्रचार करा के उसने स्थानीय व्यापारियों और राजनेताओं का समर्थन पाने की कोशिश की।

फिर पुलिस की गिरफ्त में : इस दौरान वह मछुआरों से भी मिलने-जुलने जाता रहा। वहां वह जिस बंगले में रुका, उसका नाम उसने 'व्हाइट हाउस' रखा। दिसंबर, १९८७ में वह फिर वहां से गायब हुआ और १४ फरवरी, १९८८ को बंबई से जखाऊ लौटा। पुलिस को भनक लगी कि १७ फरवरी को वह फिर चंपत होने के चक्कर में है और जैसे ही टैक्सी उसे लेने पहुंची उसे धर दबोचा गया। उसके पास से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के नक्शे तथा ब्लू-प्रिंट मिले। उसके घर से कम-से-कम पांच लाख रुपए की किताबें मिलीं। इस बार उसके साथ एक २५ वर्षीय लड़की कोरिना परेरा थी। बंबई की यह लड़की कुछ समय से उसके साथ थी। पहले वह इसे अपनी पत्नी बताता रहा, पर बाद में इस लड़की ने स्वीकार किया कि शामजी ने उसे अपना सचिव नियुक्त किया था।

१९ फरवरी को उसे सरकारी गोपनीयता कानून की धारा (१) बीसी ९ और १२ के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसे नखतराना कोर्ट में पेश किया गया। इस बार उसके पास मिले दस्तावेजों से उसके अमरीकी गुप्तचर संस्था सीआईए, बंबई के अपराधियों के सरगंना, अरब के अमीरों, कुछ प्रमुख राजनेताओं और कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों से रिश्तों का पता भी चला। उसके पास कच्छ को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अलग करने की योजना का प्रारूप भी मिला।

अमरीकी सेना के कुछ अवकाशप्राप्त अधिकारियों जो अब भाड़े के सिपाहियों का धंधा करते हैं, से भी उसके रिश्ते थे। सर्वाधिक संदेह को जन्म देने वाला तथ्य यह था कि उसके साथ हुए पत्र-व्यवहार में कुछ संकेताक्षरों का प्रयोग हुआ है। गुप्तचर व्यवस्था में काम करने वालों के अनुसार भाड़े के जत्थे सीआईए के लिए ही काम करते हैं। इन सभी कागजात से एक बात साफ है कि शामजी को रूस की हर चीज से नफरत है।

कमर्शियल पाइलट का लाइसेंसधारी शामजी साठ के दशक के शुरू में विमान चलाने के काम के सिलसिले में ही अमरीका गया था। सत्तर के दशक में अरब अमीरों का विमान चलाने के क्रम में ही वह शारजाह पहुंचा। यहीं अमरीकी सेना के अवकाशप्राप्त मेजर डेनियल डिक्सबी श्वार्ट्ज से भेंट हुई जो अब न्यूयार्क में डिक्सबी मैनेजमेंट कार्पोरेशन चलाता है। शामजी ने अपनी स्वतंत्र कच्छ वाली योजना के लिए इसी डिक्सबी से संपर्क जोड़ा।

सीआईए संपर्क : डिक्सबी का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। वह पहले अमरीकी सेना की गुप्तचर शाखा का मेजर था और सुदूर पूर्व के मामलों पर नजर रखता था। बाद में अवकाशप्राप्त करने पर उसने अपनी कंपनी बना थी। राष्ट्रपति और न्यूयार्क के गवर्नर का चुनाव लड़कर उसने पर्याप्त चर्चा पायी और इससे कारोबार बढ़ाने में मदद मिली। वह अंग्रेजी के अलावा स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, चीनी और जापानी भाषाएं भी जानता है।

डिक्सबी बंबई भी आया था और वह
ताज़महल होटल में रुका था। यहीं शामजी उस
मिला और दोनों के बीच कुछ सहमति हुई। हाईको
के वकील ज़ेआर बराहिया भी इस दौरा
मौजूद थे।

लेकिन शामजी का सिर्फ डिक्सबी से
रिश्ता नहीं था। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट आ
मिलिटरी स्टडीज चलाने वाले ले० कर्नल फ्रेडरि
एच प्लैंक से भी उसके रिश्ते थे। १३ नवंबर
१९८६ को उसे लिखी अपनी चिट्ठी में प्लैंक ने ब
साफ शब्दों में कहा है कि आप अन्य जगहों पर ज
कर रहे हैं, वह हमें पता है, लेकिन इससे पैसे वाल
बातचीत में ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यह बात ध्या
रखिए कि हमारे 'खिलाड़ी' किसी उद्देश्य या गौर
को पाने के लिए यह सब नहीं कर रहे हैं। उन्हें सि
पैसे से मतलब है। स्पष्ट है कि प्लैंक के 'खिलाड़ी
भाड़े के सैनिक ही हैं।

इसके अलावा वियतनाम युद्ध में हेलिकाप्ट
चलाने का अनुभव रखने वाले राबर्ट एन बुश, ला
एंजिलिस की एलिट इनकार्पोरेटेड, जो पूर्व सैनि
की फौज है, से भी उसके संबंध थे। शामजी को
लोगों से डिक्सबी ने ही परिचित कराया था। मा
जाता है कि उसी ने शामजी का परिचय मेरी चेन
भी कराया जो सीधे सीआईए से जुड़ी मानी गयी
जिस तरह से शामजी नयी कंपनी खोलने
कागजी घोषणा कर देता था, वह भी चक्कर
डालने वाला है। कहते हैं कि उसने ऐसी करीब द
भर कंपनियों की घोषणा की। उसके विजिटिंग क
में उसे शामजी एअरक्राफ्ट्स का अध्यक्ष और प्र
निदेशक बताया गया है, ऐसा शायद बड़े लोगों

> उसने जखाऊ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाने का वादा किया था। औद्योगिक परिसर बनाने, फ्लाइंग क्लब, भुज को अहमदाबाद और बंबई से जोड़नेवाली निजी विमान सेवा तथा अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का खूब प्रचार कराके उसने स्थानीय व्यापारियों और राजनेताओं का समर्थन पाने की कोशिश की।

शामजी का कहना है

"वे लोग मुझसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाये हैं, इसलिए उन्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये नक्शे तो देशभर में दर्जनों के भाव मिल जायेंगे। और फिर आप विमान उड़ानेवाले के पास और क्या पायेंगे? मैं एक पाइलट हूं।"

ये बातें कही हैं, कैप्टन शामजी वीरजी छेड़ा ने। गिरफ्तारी के बाद उसने जो कुछ भोगा है, उससे उसकी मजाक करने की आदत और पुलिस तथा गुप्तचर विभाग के लोगों के प्रति उसके मन में जमी बैठी भावना में कोई बदलाव नहीं आया है।

भुज जेल में पड़े इस कैदी से पूछा गया, "अगर सरकार तुमको दोषी न पाकर छोड़ दे, तो क्या करोगे?" जवाब में उसने कहा, "पुलिस के माध्यम से सरकार ने मुझे जितना परेशान किया है, उससे कच्छ के प्रति मेरा स्नेह समाप्त हो गया है।" थोड़ा रुककर वह बोला, "अगर कच्छ के विकास की मेरी योजना कोई खरीदना चाहेगा, तो मैं उसे बेच दूंगा।"

छेड़ा का कहना है, "मेरा देश मूर्खों का देश है। यहां के विकास के लिए आपको सिर्फ दिमाग की जरूरत है। अगर समुद्र तट पर न्यूयार्क और बंबई जैसे अनेक शहर फूल-फल सकते हैं, तो कच्छ का जिखाऊ क्यों नहीं विकसित हो सकता?"

शामजी रूस के खिलाफ जहर उगलने लगता है, "पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान की तरह रूस एक दिन भारत को भी निगल जायेगा। मुझे तब कोई आश्चर्य नहीं होगा जब देश के मौजूदा नेता, ओमन द्वारा मुशीरा द्वीप समूह रूस को सौंपे जाने की तरह, कच्छ को भी उसके हवाले कर देंगे। रूस के पास गर्म पानीवाला कोई बंदरगाह भी नहीं है। इसलिए वे कच्छ को ही मागेंगे।"

◆

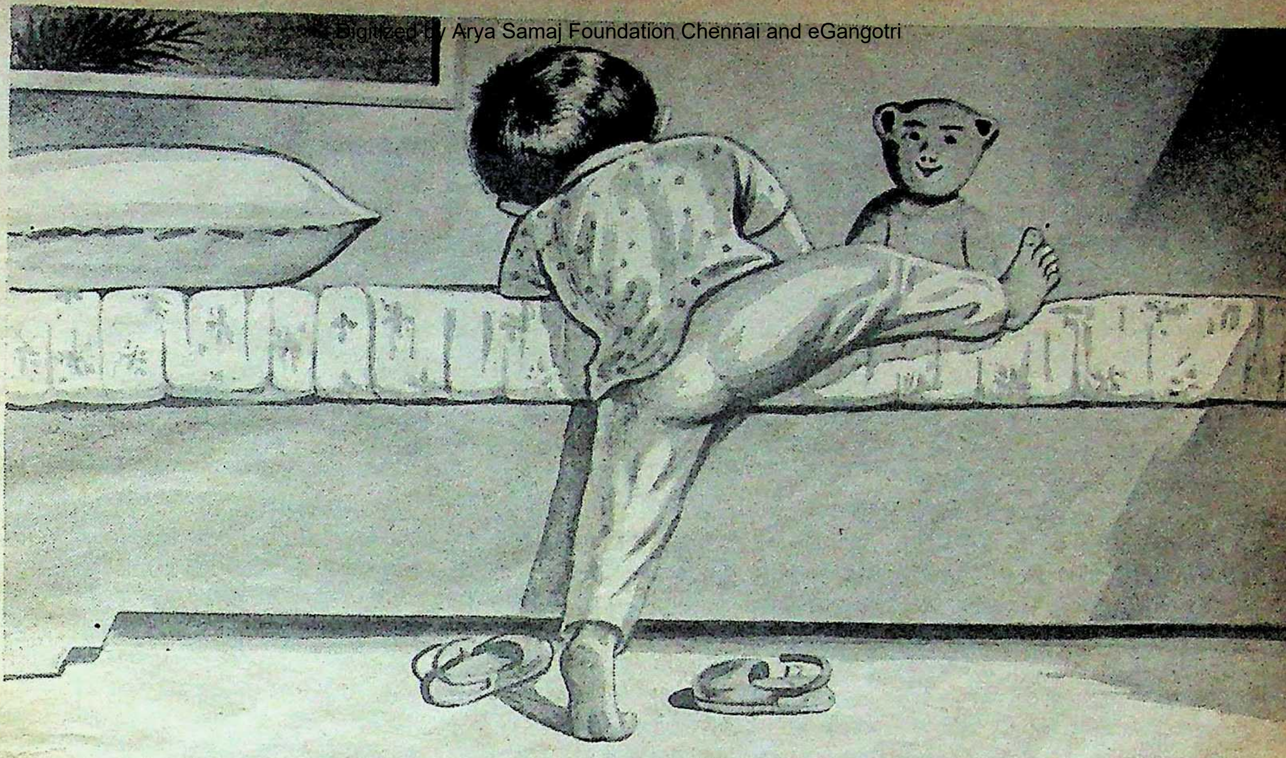

यह ध्यान रखें कि वह एक सुरक्षित गद्दे पर ही सो रहा है ...न कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गद्दे पर।

यदि वह त्वचा रोग, खारिश-खुजली, खांसी या छींकों, दुखती आँखों या वहती नाक से परेशान है, तो हो सकता है कि वह जिस गद्दे पर सोता है उसमें विषैले रसायनों का प्रयोग किया गया हो, उसमें धूल या मिट्टी हो सकती है,खटमलों तथा अन्य अनेक कीटाणु, कीड़े-मकोड़ों ने उस गद्दे में अपना ठिकाना बना लिया हो।

किन्तु अब आप इन सब से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं।

टोटोफोम पूर्णतः साफ-सुथरा है

'टोटोफोम' गद्दे प्राकृतिक रबड़ से बनाए जाते हैं। इसमें प्रयुक्त लेटेक्स अधिक मात्रा में होने के कारण हाइड्रोएक्सट्रेक्टर प्रक्रिया द्वारा इसे अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा किया जाता है। यह प्रक्रिया इसे एक ऐसा एकमात्र गद्दा बनाती है जो कि पूर्णतः साफ-सुथरा और रसायन-मुक्त है जिसे आप निःसंकोच खरीद सकते हैं।

टोटोफोम में रूई और नारियल (क्वायर) के रेशे आदि नहीं है। खटमल,कीड़े-मकोड़े प्रवेश नहीं कर सकते और न पैदा होकर मर या सड़ सकते हैं। टोटोफोम:फैक्ट्री से आपके पास पूरी तरह साफ-सुथरा आता है और सदा साफ ही रहता है।

टोटोफोम पूर्णतः सुरक्षित है

प्राकृतिक रबड़ से निर्मित टोटोफोम से कभी त्वचा पर खरोंचे नहीं पड़ती और न ही अन्य दूसरी किस्म के (गैर-रबड़) गद्दों की तरह सख्त और बेआरामदायक होता है। गैर-रबड़ गद्दों में उपरोक्त खूबियाँ गिनाई जाती है किन्तु इन खूबियों का आधार होता है, काफी घातक कृत्रिम पी.यू.फोम जिसकी एक पतली पर्त अन्य किस्म के (गैर-रबड़) गद्दों के ऊपर चिपकाई जाती है या पी.यू. फोम की एक पतली किविलटिड कवर के अन्दर लगा कर उसकी वास्तविकता छुपा दी जाती है।

ब्रिटेन में तो सिन्थैटिक पी.यू. फोम का इस्तेमाल गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।"*.. ब्रिटेन में वर्ष में कम से कम 300 व्यक्ति मरते हैं... अतिशय ज्वलनशील पॉलिमरयेन (कृत्रिम पी.यू. फोम) की हाइड्रोजन साइनाइड की भनक से... अल्पावधिक प्रभाव ही (गैस के लिए) अपने आप में मृत्यु का एक बड़ा कारण है।*" [टाइम्स आफ इंडिया, 17 जनवरी 1988]

जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके जीवन से खिलवाड़ न करें। अपने घर में टोटोफोम लाए।

टोटो फोम पूर्णतः आरामदायक है

प्रयोग करने वाले टोटो फोम गद्दे से पूरे शरीर को मिलने वाले आराम तथा रात भर गहरी, मीठी और हर सुबह तरोताजा उठाने वाली नींद के दीवाने है। यानी सिर्फ टोटोफोम के दिवाने है। इसमें प्रयुक्त अधिक मात्रा में लेटेक्स आपके शरीर के अलग-अलग अंगों को स्वतंत्र रूप से समायोजित करता है ताकि प्रत्येक अंग को विशिष्टतः उतना ही अवलंबन मिल सके जितने की उसको आवश्यकता है... न अधिक सख्त... न अधिक मुलायम... एकदम सही और संतुलित।

साफ-सुथरा,सुरक्षित,आरामदायक! केवल 'टोटोफोम' ही ईमानदारी से इन तीनों खूबियाँ से परिपूर्ण गद्दे उपलब्ध करता है।

TOTOFOAM

Comfortable. Clean. Chemical-free.

Made with natural rubber

अजन्ता रबर

ऑफिस व शोरूम :
90 पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली
फोन : 310554 टेलेक्स : 31-77036 HPL IN

TOTO FOAM • मेट्रेसिज • कुशंस् • तकिये • बस सीट्स • ट्रैक्टर सीट्स • सिनेमा सीट्स • विमान सीट्स TOTO FOAM

Hitads

रोब गालिब करने के लिए किया जाता था।

इसके साथ ही कच्छ और बंबई में रहने के दौरान उसकी जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। जब वह कच्छ में होता था, तो महंगे होटलों में रहता था, हवाई ज़हाज और कारों से ही यात्रा करता था। शानदार पार्टियां देता था, जबकि बंबई में वह लोकल ट्रेन से चलता था और वह भी पास से।

खोजबीन से पता चलता है कि उसने अब्दासा के समुद्र तट की जमीन पर निजी हवाई अड्डा, बंदरगाह और आधुनिक उपनगर बसाने की अनुमति के लिए अर्जी दी थी। साथ ही उसने काडला हवाई अड्डे से लगी काफी जमीन खरीद ली है और वहां वह हेलिकाप्टर का अड्डा बनाना चाहता है। फ्लोरिडा के एक नगर नियोजक से उसने नया नगर बसाने की योजना भी बनवायी थी।

कच्छ के जिला पुलिस प्रमुख आरआर विलियम्स के अनुसार शामजी बहुत तेज आदमी है और वह दुनिया के किसी भी विषय पर घंटों बात कर सकता है, जबकि विमानन उसका खास विषय है। विलियम्स ने कहा, "हमें पूरा भरोसा था कि शामजी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मामला चल सकता है।"

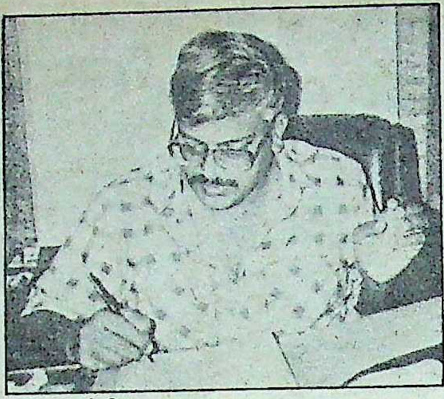

आरआर विलियम्स

गिरफ्तारी के बाद शामजी से काफी कड़ाई के साथ पूछताछ भी की गयी। २२ दिनों तक सेना, सीमा सुरक्षा बल, रॉ और राज्य पुलिस के लोग उससे पूछताछ करते रहे। इस दौरान उसने क्या कुछ उगला, इसका ठीक पता तो नहीं है, लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार पूछताछ करनेवाले उससे बहुत कुछ उगलवा नहीं पाये। इन दस्तों के साथ गये मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि शामजी बहुत शातिर है। जैसे उसने अपनी विदेश यात्रा के बारे में सारी जानकारियों को सिर्फ एक कथन से 'धो' दिया कि उसका पासपोर्ट फट-फटा कर खतम हो गया है और जांच करने वाले इस बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाये।

कच्छ के जिला पुलिस प्रमुख आरआर विलियम्स के अनुसार शामजी बहुत तेज आदमी है और वह दुनिया के किसी भी विषय पर घंटों बात कर सकता है, जबकि विमानन उसका खास विषय है।

शामजी को झूठ पकड़ने वाली मशीन के आगे भी बिठाया गया। यहां वह उलटे-सीधे बयान देकर बचता रहा। अमरीकी लोगों और संस्थाओं से किसी भी तरह के संबंध के बारे में पूछने पर उसका सीधा जवाब होता था, 'नहीं'। फिर उसका नारको-डिटेक्टिव टेस्ट (जो अधिक विकसित है) करने का सुझाव दिया गया। लेकिन शरीर में दवा घुसाकर की जाने वाली इस जांच के लिए सरकार और अदालत की अनुमति जरूरी है। इसमें काफी वक्त लगा और हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि इस अवस्था में सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही सवाल पूछ सकते हैं, वहां पुलिस के लोग न रहें। सितंबर में हुए इस टेस्ट में भी कुछ खास तथ्य नहीं उगलवाये जा सके और जांच की रिपोर्ट में कहा गया कि वह बहुत बड़ा शातिर है और बोलकर बच निकलता है।

इस बीच कच्छ पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन का मामला बनाया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया है। इस मसले पर केंद्र की स्वीकृति के बाद ही अदालती कार्रवाई शुरू हो सकेगी। लेकिन खुद पुलिस के ही कुछ बड़े अधिकारियों को संदेह है कि इस मामले में सफलता नहीं मिलेगी।

दूसरी ओर इस सारे प्रकरण के बाद भी कच्छ का आम आदमी मानता है कि शामजी कच्छ को विकसित करने की अपनी योजना की कीमत चुका रहा है। इंका के पूर्व सांसद महिपत मेहता ने भी पिछले साल मार्च में आयोजित एक सभा में शामजी की योजना की तारीफ की थी। उसको 'यातना' देने की खबर मुखपृष्ठ पर छापने वाले साप्ताहिक की प्रतियां खूब बिक और बंट रही हैं। उधर कच्छ को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है।

लेकिन पिछले एक दशक से इस इलाके की सारी घटनाओं पर नजर रखने वाले कच्छ पुलिस के अधिकारी मानते हैं कि शामजी सिर्फ इस इलाके का विकास करने का ख्वाब देखने वाला आदमी नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ पूरी जांच करके मुकदमा चला पाने के मामले में वे अपने को असमर्थ और साधनहीन मानते हैं।

—आरके मिश्र

शामजी की चिट्ठी

अमरीका स्थित इंस्टीट्यूट आफ मिलिटरी स्टडीज के फ्रेडरिक प्लैंक को लिखित शामजी की चिट्ठी के अंश, जिस पर कोई तारीख नहीं पड़ी है :

"जवाब में देर के लिए माफ करेंगे। आपकी १६ जुलाई, फिर बिना तारीखवाली चिट्ठियां मिलीं थीं और १३ अक्तूबर, १९८६ वाली चिट्ठी आज मिली।

देरी इस कारण हुई कि मैं अपनी द्वीपवाली योजना को द्वीप राष्ट्र की योजना में बदल रहा हूं और इस संबंध में कुछ सामान आपको कल भेजे जा रहे हैं। मैं आपके अध्ययन के लिए कुछ और चीजें भेजूंगा, ताकि आप दो वर्षों में मेरी जरूरत के 'खिलौनों' और 'पर्यटकों' के बारे में अनुमान लगा सकें।

कोषागार में अभी चार अरब अमरीकी डालर जमा हो रहे हैं, जिससे पहले बसनेवालों का इंतजाम हो। शुरू में काफी जानकार २०००० प्रवासी लोगों को ही बुला रहा हूं। दूसरे चरण में २००००० लोग आयेंगे और वे सभी श्वेत लोग होंगे।

मुझे यह बतायें कि क्या आप वियतनाम या उससे पहले कोरिया युद्ध में शामिल थे? कुछ दिन पहले मैं एक टेप सुन रहा था जिससे पता चला कि अमरीका के पुराने सैनिक, उन जगहों पर रह गये करीब ११०० लोगों को वापस बुलाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात में है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? मेरे द्वीप के लिए यह अच्छा होगा। वियतनाम ग्रुप के किसी को मैं नहीं जानता। वहां की नवीनतम खबर क्या है?

भारत में तो रूसी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, और जिस तरह से नेताओं का व्यवहार है, मुझे पूरा विश्वास है कि १९९० तक भारत दूसरा अफगानिस्तान बन जायेगा। इसलिए द्वीप राष्ट्र बनाने और प्रवासियों को बसाने के लिए हमारे पास दो साल का समय ही है। यहां सारे कानून अमरीका की तरह होंगे, पर राजवंश चलेगा, उसी के नाम से सिक्के चलेंगे।

एक क्षण के लिए मैंने सोचा था कि आप भी 'कंपनी' में शामिल होकर निकारगुआ के प्रशिक्षण अभियान में चले गये हैं।

मैं मध्य पूर्व और मलेशिया में विमान का कारखाना लगा रहा हूं। इससे भी काफी मदद मिलेगी।

इस राष्ट्र का नाम जल्दी ही घोषित होगा और आपको इसकी सूचना दे दी जायेगी। अन्य चीजें भी छप रही हैं और निकट भविष्य में आपको भेज दी जायेंगी। यहां की सुरक्षा का इंतजाम आपको सौंपा जायेगा।

अच्छा, क्या आपको पता है कि जुआवाला कैसिनो उपकरण कहां से लिया जा सकता है? अमरीका से साफ-सुथरे डीसी-३ मिलने की कितनी संभावना है और इस पर क्या खर्च आयेगा?

कृपया अपना खयाल रखिए और प्रस्तावित यात्रा के बारे में सूचना मिलने का इंतजार कीजिए।

आपका विश्वसनीय

शामजी

◆

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 111151

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

ऊसर व्यवस्था की जद में

अनियमितताओं का अंबार: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

पच्चीस वर्ष पूर्व जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि यह कृषि विषयक शिक्षा देने के साथ-साथ उन्नत बीजों और कृषि-प्रौद्योगिकी का विकास भी करेगा, लेकिन आज यह विश्वविद्यालय ऐसी अनियमितता और दुरव्यवस्था का शिकार कैसे हो गया कि न केवल यहां घटिया बीजों का उत्पादन और उत्तरपुस्तिकाओं में घोटाले हो रहे हैं, बल्कि खुद कुलपति की नियुक्ति ही विवादास्पद बन गयी है?

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में २ अक्तूबर, १९६४ को विशेष प्रयोजनों से की गयी थी। विवि को यह दायित्व सौंपा गया था कि वह छात्रों, कृषकों और अनुसंधानकर्ताओं को औपचारिक शिक्षा देने के साथ-साथ समुचित कृषि-प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगा और कार्यकर्ताओं को इस प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मप्र शासन, इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अनेक भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे मुक्तहस्त सहायता प्रदान की। जबलपुर में कृषि विवि की स्थापना पिछड़े और कृषिप्रधान मध्यप्रदेश के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था। १९८७ में रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विवि की स्थापना तक यह देश के इस विशालतम प्रदेश में इकलौता कृषि विवि था। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सात कृषि महाविद्यालय (जबलपुर, रीवा, खंडवा, सीहोर, इंदौर, मंदसौर और ग्वालियर), दो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय (जबलपुर और महू) तथा एक कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय (जबलपुर) इसमें समाविष्ट हैं तथा इसका वार्षिक बजट दस से बारह करोड़ रुपयों के बीच है। तीस अनुसंधान केंद्रों के जरिये इसका चार-स्तरीय अनुसंधान संजाल समूचे प्रदेश में फैला हुआ है।

स्थापना के बाद कई सालों तक विवि सुचारु और नियोजित रूप से चलता रहा और इसकी ओर किसी ने उंगली नहीं उठायी। परंतु शनैः-शनैः इसे बखेड़ों ने अपनी गुंजलक में कैद कर लिया और विवि अनियमितताओं, राजनीतिक हस्तक्षेप और दुरव्यवस्था का शिकार हो गया।

कुलपति का चयन: कृषि विवि के कुलपति पद पर इस समय आसीन डा॰ डीके शर्मा इस नाते विवादास्पद कुलपति हैं कि उनके चयन को अवैधानिक बताते हुए न्यायालय तक में चुनौती दी गयी है, किंतु विवादों से घिरनेवाले वे पहले शीर्षस्थ अधिकारी नहीं हैं। यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को सही माना जाये, तो पूर्व कुलपति चंद्रिका ठाकुर को तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य मनोमालिन्य के चलते पद से हटना पड़ा था। उनके हटने पर कुरसी हथियाने के लिए लंबा और गहरा शीतयुद्ध चला था। तब पद के दो प्रमुख दावेदार थे: प्रो॰ आर्य और डा॰ डीके शर्मा। प्रो॰ आर्य के लिए उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता की सिफारिश डा॰ शर्मा के लिए अलंघ्य व्यवधान बन गयी और आर्य ने बाजी मार ली। शर्मा मन मसोस कर रह गये। अधीर प्रतीक्षा और सघन प्रयासों के बाद डा॰ शर्मा को अप्रैल '८७ में मौका मिला और प्रो॰ आर्य को अप्रैल '८७ में मौका मिला और प्रो॰ आर्य की सेवानिवृत्ति के बाद वे कुलपति चुने गये।

डा॰ शर्मा को कुलपति बने जुम्मा-जुम्मा आठ रोज ही हुए थे कि जबलपुर के एक अधिवक्ता प्रमोद गुप्ता ने मप्र उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। गुप्ता के वकील पूर्व महाधिवक्ता सुरेंद्र दीक्षित ने याचिका में कहा है कि चयन समिति की

१८॥११

साक्षात्कार : डा० डी के शर्मा

सब पूर्व कुलपति की मेहरबानी है

कृषि, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी की औपचारिक-शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए २५ वर्ष पूर्व स्थापित जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि इन दिनों दो विद्वानों की अवांछित प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बना हुआ है। कभी इस विवि को मध्यप्रदेश का गौरव समझा जाता था, किंतु विगत लगभग एक दशक में विवि के परिसर में व्याप्त प्रवृत्तियों और घटित घटनाओं ने इसकी गरिमा को कलुषित और खंडित करने में कोई कोरकसर नहीं उठा रखी है। विवि के प्रारंभिक कुलपतियों—डा० जेएस पटेल और डा० नेगी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके हाथों पुष्पित-पल्लवित यह विवि आगे चलकर अनियमितताओं की गिरफ्त में आ जायेगा। इसे वर्तमान कुलपति का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि उन्हे पद पर बैठने के क्षण से ही विवादों व आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत हैं, जबलपुर में डा० शर्मा से हुई लंबी बातचीत के मुख्य अंश :

माया : आपका कुलपति पद पर चयन विवादास्पद रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि तीन सदस्यीय चयन समिति में दो आपके रिश्तेदार थे?

शर्मा : *जी नहीं। डा० रिछारिया जरूर हमारे समधी हैं। उनके बेटे को हमने अपनी बेटी दी है। किंतु डा० आचार्य हमारे रिश्तेदार नहीं हैं।*

माया : उत्तरपुस्तिकाओं में हेराफेरी का प्रकरण प्रकाश में आया है। चार छात्रों के अंक थोक में बढ़ाये गये हैं। इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं?

शर्मा : *देखिये, हमें आये तब एक दो महीने ही हुए थे, जबकि यह खेल काफी पहले से चला आ रहा था। मेरा विचार है कि कुछ छात्रों ने उत्तरपुस्तिकाओं की अलमारी की नकली चाबी बनवा रखी थी और कर्मचारियों की उनसे मिलीभगत थी। इस मामले में हम निष्क्रिय नहीं रहे, वरन हमने तत्परता से कार्रवाई की। डा० गौर का स्थानांतरण किया गया। इसमें पूरी तौर पर क्या घपलेबाजी हुई, मैं समझ नहीं सका हूं।*

माया : परंतु डा० गौर तो मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोषी कोई और है। उन्हें अकारण दंडित किया गया है?

शर्मा : *इस मसले की सीबीआई जैसी संस्था भला क्या जांच करेगी? और डा० गौर उसके प्रभारी थे। क्या वे इससे इनकार करते हैं कि वे प्रभारी नहीं थे।*

माया : क्या यह सही है कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण विवि पर करीब तीन करोड़ रुपयों का ओवरड्राफ्ट है?

"यह सब हमारे पूर्वकुलपति की मेहरबानी है। मैं कितना भी अच्छा काम क्यों न करूं, वे ऐसा ही कहेंगे। जो भी विरोधी हैं, सारे-के-सारे उन्हीं के आदमी हैं। वे निराधार और अनर्गल बातें फैलाते हैं।"

शर्मा : *जब हमने पदभार ग्रहण किया, तब भी विवि पर ओवरड्राफ्ट था जो चार करोड़ के ऊपर पहुंच गया था। हमने तो इसे घटाकर अब लाखों में ला दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।*

माया : आपने भारीभरकम ओवरड्राफ्ट भला किस जादू की छड़ी से कम किया?

शर्मा : *जादू की छड़ी नहीं, सूझबूझ से। पहले मप्र सरकार से जैसी सहायता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। उसके लिए मैं स्वयं भोपाल जाकर मुख्यमंत्रीजी से मिला। उन्हें वस्तुस्थिति बतायी। काफी परेशानियां उठायीं। तब कहीं जाकर राज्य सरकार ने सहायता देना प्रारंभ किया। इस सहायता से और संस्थान को सुचारु रूप से चलाने से ही ओवरड्राफ्ट में कमी संभव हो सकी है।*

माया : पिछले दिनों विवि की परियोजना की कई गायें मर गयीं। बीच में गायों को कसाइयों को नीलाम करने का भी फैसला हुआ था। क्या यह ज्ञात हुआ कि गायें चारे के अभाव या किसी बीमारी से मरी थीं?

शर्मा : *यह सरासर गलत है कि मेरे काल में कोई गाय कसाइयों को बेची गयी है। गायों की नीलामी का फैसला मेरे काल की बात नहीं है। गायों के बड़ी संख्या में मरने की बात भी गलत है। एक-एक, दो-दो गायें कुछ समय के अंतराल में मरी हैं। मेरे पूर्व कुलपति महोदय ने नियुक्तियां इतनी ज्यादा कर दी थीं कि उन्हें रखने और काम देने की समस्या उठ खड़ी हुई थी, वेतन तो बाद की बात है। नब्बे आदमी गायों की रखवाली के लिए रखे गये, जबकि इतने बड़े अमले की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें वहां से हटाकर अन्यत्र काम में लगाया और विवि को आमदनी का जरिया दिया। इस समय मात्र ३० कर्मचारी गायों की देखभाल आदि का काम कर रहे हैं। बाकी को डेयरी परियोजना से हटा दिया गया है। डेयरी परियोजना में ६० लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं थी।*

माया : आपके आईआर-३६ और सी-३०६ ब्रीडर बीजों को अनुपयुक्त घोषित किया गया। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है?

शर्मा : *नहीं, इस साल तो हमारे सारे बीज लिये गये हैं। पिछले वर्ष धान का आईआर-३६ बीज जरूर नहीं लिया गया था। बीज विकास निगम ने जिसे अनुपयुक्त बताया, उसमें भी कोई खास खराबी नहीं थी। जमीन में जरूर कुछ खराबी थी।*

माया : जबलपुर में विवि के प्रक्षेत्र में क्या कारण है कि औसत उत्पादन अन्य जगहों से कम हुआ है, जबकि सीधे नियंत्रण व निगरानी के कारण यहां अधिक उत्पादन होना चाहिए था?

शर्मा : *नहीं, यहां का औसत उत्पादन कतई कम नहीं है। धान का कुछ कम उत्पादन होने का कारण सूखा पड़ना है। गेहूं तो और जगहों से ज्यादा हुआ है।*

माया : दूध के औसत उत्पादन के बारे में क्या कहेंगे?

शर्मा : *उत्पादन बढ़ा है। प्रति गाय औसतन दस किलो दूध का उत्पादन हो रहा है। पहले यह दस से कम था।*

माया : आपके हिसाब से सारे कामों में प्रगति हुई है। फिर क्या कारण है कि विभागों में असंतोष है, शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि अनियमितताएं हैं और कुलपति की तानाशाही चल रही है?

शर्मा : *यह सब हमारे पूर्व कुलपति की मेहरबानी है। मैं कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करूं, वे ऐसा ही कहेंगे। जो भी विरोधी हैं, सारे-के-सारे उन्हीं के आदमी हैं। वे निराधार और अनर्गल बातें फैलाते रहते हैं।*

—एसपी त्रिपाठी

अंक घोटाले का तथ्य

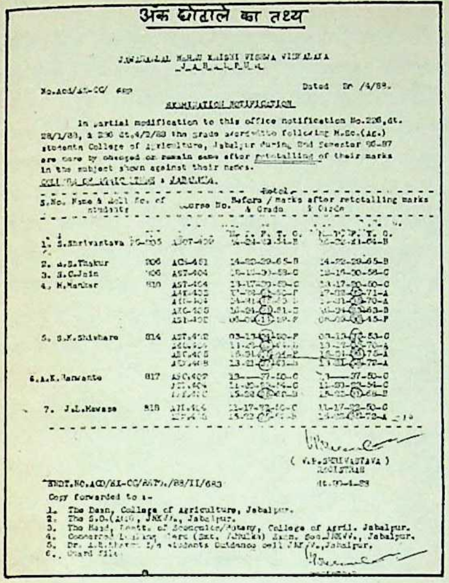

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
J A B A L P U R

No.Acd/[illegible]
Dated [illegible] /4/88.

EXAMINATION NOTIFICATION

In partial modification to this office notification No.226,dt. 28/1/88, & 230 dt.4/2/88 the grade [illegible] following M.Sc.(Ag.) students College of Agriculture, Jabalpur during 2nd Semester 86-87 are here by changed or remain same after retotalling of their marks in the subject shown against their names.

S.No.	Name & Roll No. of students		Course No.	Before / marks after retotalling & Grade	marks & Grade
1.	S.Shrivastava				
2.	A.S.Thakur	806			
3.	S.C.Jain		AST-404		
4.	M.Mankar	810	AST-404		
5.	S.K.Shivhare	814			
6.	A.K.Hanwante	817			
7.	J.L.Mawase	818			

(V.P.SHRIVASTAVA)
REGISTRAR

ENDT.NO.ACD/[illegible]/88/II/683

Copy forwarded to :-

1. The Dean, College of Agriculture, Jabalpur.
2. The S.O.([illegible]), JNKVV., Jabalpur.
3. The Head, Deptt. of [illegible], College of Agril. Jabalpur.
4. [illegible] JNKVV., Jabalpur.
5. Dr. [illegible] I/c students Guidance cell JNKVV.,Jabalpur.
6. Guard file

अनुशंसा अवैधानिक व न्याय के प्रतिकूल है तथा डा० शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है। इस याचिका में कृषि सचिव, मप्र शासन, कुलपति कृषि विवि, एमबी राव उपमहानिदेशक, इंकौं आफ एरि नयी दिल्ली, धान अनुसंधान संस्थान, रायपुर के पूर्व संचालक डा० आरसी रिछारिया और श्रीवास्तव रजिस्ट्रार, कृषि विवि को प्रतिवादी बनाया गया है। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिद्वय सीपी सेन व वायसी सूर्यवंशी ने इस याचिका की सुनवायी कर कारण बताओ नोटिस जारी की है और यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

चयन समिति की अनुशंसा को अवैधानिक निरूपित करने की कथा इस प्रकार है: १९८७ में कुलपति के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे, आरसी रिछारिया, केसीएस आचार्य और एमबी राव। उपर्युक्त याचिका में कहा गया है कि चयन समिति के दो सदस्य डा० रिछारिया और आचार्य (पूर्व मुख्यसचिव, मप्र शासन) डा० शर्मा के निकट संबंधी हैं। डा० रिछारिया डा० शर्मा के समधी और आचार्य नजदीकी रिश्तेदार बताये गये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलपति की पुत्री कल्पना का विवाह रिछारिया के पुत्र माधवेंद्र रिछारिया से हुआ है व आचार्य रिछारिया के समधी हैं। इस प्रकार दो समधियों ने मिलकर तीसरे समधी का कुलपति के सम्मानित पद के लिए चयन किया।

उत्तर पुस्तिका प्रकरण : अतीत में अंकसूची प्रकरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निलंगेकर और मप्र के शिक्षामंत्री चित्रकांत जायसवाल के खाते में अपयश दर्ज कर चुका है। इस लिहाज से कृषि विवि का उत्तरपुस्तिका प्रकरण विवि की छवि को कलुषित करने के लिए पर्याप्त है। उत्तरपुस्तिका प्रकरण इस मायने में गंभीर है कि इसमें एक साथ चार छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं में हेराफेरी हुई और थोक के भाव अंक बढ़ाये गये। उत्तरपुस्तिकाओं में हेराफेरी, पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बहाने की गयी। इसका उद्घाटन तब हुआ,जब रजिस्ट्रार, बीवी श्रीवास्तव ने २० अप्रैल '८८ को आदेश क्रमांक सीसी १६८२ के तहत एमएससी कृषि (द्वितीय सेमिस्टर) सत्र ८६-८७ के छात्रों का पुनर्मूल्यांकन के बाद परीक्षाफल घोषित किया। इसमें सात छात्रों के सत्रह विषयों का परीक्षाफल घोषित हुआ। छात्रों के अंकों में ४ से ३७ अंकों तक वृद्धि हुई। यह आश्चर्यजनक था कि किसी छात्र के एक साथ ३७ अंक बढ़ जायें अथवा उसके तीन विषयों में अंकों में बढ़ोतरी हो और उसे सर्वोत्तम 'ए' ग्रेड मिल जाये।

अंकों में थोक वृद्धि का राज यह था कि छात्रों ने बंद ताले की अलमारियों में रखी अपनी उत्तरपुस्तिकाएं वहां से उड़ाकर भीतर के पन्ने बदल दिये थे। पर्दाफाश तब हुआ, जब उत्तरपुस्तिकाएं पुनर्मूल्यांकन के लिए, नये मुखपृष्ठ जुड़ने के बाद, अध्यापकों के पास पहुंचीं। एक अध्यापक ने पाया कि मुखपृष्ठ पर अंकित प्रश्नों व अंकों के क्रम भीतर हल किये प्रश्नो व प्रदत्त अंकों से भिन्न हैं। वस्तुत: उत्तरपुस्तिकाओं में व्यवस्था रहती है कि यह ज्ञात हो सके कि छात्र ने किस क्रम से प्रश्न हल किये हैं और उनमें क्रम से कितने अंक मिले हैं। छात्रों ने अंदरूनी पन्ने तो बदले, किंतु मुखपृष्ठ की व्यवस्था ने उनके किये-धरे पर पानी फेर दिया। हेराफेरी की पोल खुलते ही हंगामा मच गया। कृषि विवि के अधिष्ठाता ने ४ मई '८८ को डा० एसके अग्रवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया। अग्रवाल की जांच ने इसकी पुष्टि की कि अंकों में हेराफेरी के साथ-साथ भीतर के पन्ने भी बदले गये हैं। बदले गये पन्नों में पूरे पांच प्रश्न हल किये गये और उत्तर भलीभांति लिखे गये, लेकिन मुखपृष्ठ की अचूक व्यवस्था ने घोटाले को उजागर कर दिया।

ऐसा लगता है कि उत्तरपुस्तिकाओं में हेराफेरी कर पुनर्मूल्यांकन के जरिये अंक बढ़वाने का सिलसिला विवि में काफी पहले से चल रहा था। इसमें छात्रों के साथ चौकीदार और कुछ

अंक घोटाले का विवरण

छात्र का नाम	कोर्स	पूर्व प्राप्तांक	परिवर्तित अंक	परिवर्तन का प्रतिशत
पुनर्गणना में :				
१. एम मंकर अनुक्रमांक ८१०	ए ई एक्स ४०३	२१	३२	२२
	ए ई सी ४०४	२५	३५	२०
	ए ई सी ४०५	२१	२३	४
	ए ई सी ४०२	१४	३०	३२
२. एस के शिवहरे अनुक्रमांक ८१४	ए एस टी ४०२	४	३७	६६
	ए ई सी ४०४	२६	३५	१२
	ए ई सी ४०५	५	३६	६२
	ए ई एक्स	२५	३८	२२
३. ए के हनुमंत अनुक्रमांक ८१७	ए ई एक्स ४०८	२५	३१	१२
४. जे एल मावासे अनुक्रमांक ८१८	ए ई एक्स ४०८	२५	३५	२०
पुनर्मूल्यांकन में :				
१. एम मंकर अनुक्रमांक ८१०	ए ई सी ४०२	२९	६१	३२
	ए ई सी ४०३	१९	६५	४६
२. एस के शिवहरे अनुक्रमांक ८१४	ए ई सी ४०२	२२	५६	३४
	ए ई सी ४०३	२७	६९	४२
	ए ई ४[illegible]	४८	४२.५	२२.७

अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुलपति डा० शर्मा से बातचीत इसी संदेह की पुष्टि करती है। डा० शर्मा का कहना है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण किये कुछ ही दिन हुए थे कि यह कांड हो गया। उनकी आशंका है कि छात्रों ने उत्तरपुस्तिकाओं की अलमारी की नकली चाबी बनवा रखी थी। चौकीदार या विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी के सहयोग से उन्होंने पहले तो वहां से कापियां उड़ायीं और फिर उसमें पुराने के स्थान पर नये पन्ने जोड़कर कापियों को सफायी से पुन: अल्मारी में धर दिया। डा० शर्मा का दावा है कि अब ऐसी चाक-चौबंद व्यवस्था कर ली गयी है कि आइंदा ऐसी गड़बड़ी न हो।

उपरोक्त प्रकरण में हेराफेरी से जुड़ी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा प्रभारी डा० एसएस गौर के पास सुरक्षित थीं। घोटाले के उजागर होने से डा० गौर स्वत: संदेह के घेरे में आ गये। संदेह की सुई उनकी ओर मुड़ी, किंतु आश्चर्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर मात्र उनका स्थानांतरण जबलपुर से खंडवा कर दिया गया। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के निष्कर्षों का आज तक अता-पता नहीं है। यह जांच डा० एसएन दुबे ने की थी। प्रस्तुतीकरण अधिकारी अग्रवाल ने फाइल यथासमय रजिस्ट्रार को सौंप दी थी, किंतु रजिस्ट्रार महोदय उक्त फाइल को तीन माह तक अनावश्यक तौर पर दबाये रहे। बात जब अंततोगत्वा मुख्यमंत्री तक पहुंची, तब कहीं जाकर रजिस्ट्रार ने फाइल डा० दुबे को सौंपी। जांच के नतीजे और उस पर कार्रवाई का अभी भी इंतजार है।

घटिया बीज: विवि के मुख्य दायित्वों में विपुल उत्पादन के लिए उन्नत बीजों के विकास और उन्हें किसानों तक पहुंचाने के कार्यों का समावेश है। इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि विवि को घटिया बीजों के निर्माण का दोषी पाया गया है। १९८७ मे विवि वैज्ञानिकों ने धान के नये बीज आईआर ३६ का नाभिक व प्रजनन बीज एवं गेंहू सी-३०६ का बीज उत्पादित किया। जांच में पाया गया कि विवि ने इन्हें जिस मानक का तैयार किया है, वे उस मानक के नहीं हैं, दूसरे वे रोगग्रस्त भी हैं। बीज तैयार करने में वैज्ञानिकों द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण अनुमान है कि करीब सात लाख रुपए बर्बाद हुए। विवि के कई बीजों को मानीटरिंग कमेटी ने भी उत्पादन के अयोग्य व निम्नस्तरीय पाया।

धान के आईआर-३६ बीज का उपयोग मप्र के किसान बड़े पैमानें पर करते हैं। यह बीज मूलत: मनीला (फिलिपींस) स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की देन है और उसी ने कृषि विवि को इसकी आपूर्ति की थी। विवि का दायित्व था कि वह इसे बहुगुणित (मल्टीपल) कर किसानों को मुहैया कराता। विवि ने यह जिम्मेदारी पौध प्रजनन विभाग को सौंपी थी। मप्र राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आरएस तोमर १५ नंवबर '८८ को पत्र क्रमांक क्षे०का०ज०/उत्पा/मानी/८८-८९/५२११ के माध्यम से प्रबंध संचालक को लिखा कि धान का बीज आईआर-३६ उत्पादन-योग्य नहीं है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि १९८८ के रबी मौसम में गेहूं बीज सी-३०६ का उत्पादन भी निरस्त किया गया था। पौध प्रजनन विभाग ने जिसे सी-३०६ की फसल बताया था, उसके बारे में आरआर शिवपुरिया, गेंहू प्रजल प्रजनक, पवारखेंड़ा ने जांच के बाद अभिमत दियां कि यह फसल सी-३०६ की न होकर नर्मदा-११२ की है।

कुलपति की नियुक्ति का विवाद: सुरेंद्र दीक्षित

खरीदी: जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रयुक्त सामग्री की खरीदी में घपले के मामले भी प्रकाश में आये हैं। पौध संरक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष डा० केके शर्मा द्वारा इलेक्ट्रानिक और डिजिटल बैलेंस की खरीदी में अनियमितताएं बरती गयीं। विभाग ने इलेक्ट्रानिक और डिजिटल बैलेंस क्रमश: ९९५० रुपए और १२५०० रुपए में खरीदीं। अधिक कीमत पर खरावी के बाद भी इन तुलाओं में तकनीकी खराबी पायी गयी। संचालक, अनुसंधान ने जब स्थानीय विक्रेता स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऐंड केमिकल, नेपियर टाउन, जबलपुर से पूछताछ की, तो पता चला कि इनके बाजार मूल्य क्रमश: ७७७० रुपए और ७८७५ रुपए हैं। इस मामले की विभागीय जांच के आदेश दिये गये थे, किंतु जांच के बाद की कार्रवाई का कोई पता नहीं है। इसी प्रकार पवारखेड़ा में पदस्थ डा० नेमा ने अधिक मूल्य पर इनकुलेशन चैंबरों की खरीदी की।

गायों की नीलामी: कृषि विवि में संचालित अखिल भारतीय पशु प्रजनन परियोजना १९८६ में बंद हो गयी थी। परिणामस्वरूप दुधारू पशुओं पर होनेवाला सारा व्यय विवि के कंधों पर आ पड़ा। इसके पहले तक केंद्र सरकार व अभा कृषि अुनसंधान परिषद इस व्यय को संयुक्त रूप से वहन करती थीं हालांकि, विवि विभिन्न मदों व योजनाओं पर करोड़ों की रकम फूंक रहा था, किंतु परिषद व केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने पर ये दुधारू पशु उसके लिए भारस्वरूप हो गये। तय किया गया कि गायों समेत सभी दुधारू पशुओं को कसाइयों को नीलाम कर दिया जाये। इसकी भनक जब जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और लेखकों को लगी, तो उन्होंने विवि की इस पाशविक प्रवृत्ति का विरोध किया। राज्यसभा सदस्य श्रीमती रत्नकुमारी देवी समेत प्रभावशाली एवं प्रबुद्ध वर्ग के विरोध के कारण अंतत: तत्कालीन उपकुलपति प्रो एसबी आर्य झुके और पशु [illegible] और कसाइयों के हाथों में पहुंचने से बच गये। वैसे गौर से देखा जाये, तो पशु परियोजना की दुर्गति के लिए काफी हद तक पूर्व कुलपति प्रो० आर्य जिम्मेदार हैं। गायों के दूध से विवि को करीब एक लाख रुपए की आय होती थी, किंतु प्रो आर्य के काल में परियोजना के अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया कि स्थापना व्यय सुरसा के मुंह की भांति बढ़ गया। यह खर्च बढ़ते-बढ़ते करीब नब्बे हजार तक पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि जहां एक लाख रुपयों का लाभ हो रहा था, मुनाफा घटकर बमुश्किल दस हजार रुपयों पर अटक गया।

आज भी यह शिकायत बरकरार है कि दुधारू पशुओं को कम चारा दिया जा रहा है, जिससे अनेक पशुओं ने दम तोड़ दिया है। खोजखबर के दौरान यह भी सुनने में आया कि चोरीछिपे बहुतेरे पशु नीलाम कर दिये गये हैं। अनियमितताओं का आलम यह है कि अकारण सेवामुक्त लोग अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वित्तीय अनियमितताएं इससे उजागर होती हैं कि विवि का कोष रिक्त है और वह ओवरड्राफ्ट की आक्सीजन पर जीवित है। और कुछ हो या न हो, परंतु वर्तमान कुलपति की इसके लिए सराहना करनी होगी कि उन्होंने फिजूलखर्ची पर अंकुश का सफल उपक्रम किया है। एक साल पहले तक विवि करीब साढ़े चार करोड़ रुपयों के ओवरड्राफ्ट पर चल रहा था, जिसे डा० शर्मा घटाकर करीब तीन करोड़ पर ले आये हैं। विवि और कुलपति के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा काफी बड़ा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विगत कुछ सालों में विवि अपने मूल उद्देश्यों से भटका है। विवि प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी इधर काफी बढ़ी है। व्यापक अनियमितताओं के कारण पूर्व मुख्यसचिव मदनेश्वर शरण सिंह देव की अध्यक्षता में एक कमेटी शिकायतों की जांच कर चुकी है। इसी के बरक्स वास्तविकता यह है कि विवि में पदस्थ शीर्षस्थ अधिकारी और निचला अमला भी राजनीतिक व्याधि से ग्रस्त होकर परस्पर प्रतिद्वंद्वी लाबियों में बंट गया है। डा० शर्मा के विरोध में सक्रिय लाबी को प्रो० आर्य का प्रश्रय प्राप्त बताया जाता है। विरोधी गुट जहां येन-केन-प्रकारेण पुन: कुलपति की कुरसी हथियाना चाहता है, वहीं डा० शर्मा इस पर लंबे समय तक काबिज रहने की फिराक में हैं। इसका तात्कालिक परिणाम यह हो रहा है कि विवि शिक्षा और शोध का आश्रम, मंदिर के बजाय अखाड़े का रूप लेता जा रहा है। अगर विवि परिसर में स्वस्थ प्रवृत्तियों की पुनर्स्थापना नहीं हुई और पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता पर रोक नहीं लगी, तो पं० जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए स्थापित इस विवि के नेहरू जन्मशती और अपने रजत जयंती वर्ष में और अधिक दुर्दशाग्रस्त होने की आशंका को झुठलाया नहीं जा सकता।

[illegible] त्रिपाठी 'आशु' राजेंद्र राय के सहयोग से

गये। वैसे
ी दुर्गति के
प्रो० आर्य
करीब एक
ार्य के काल
संख्या में
ापना व्यय
खर्च बढ़ते-
। परिणाम
ाभ हो रहा
रुपयों पर

ार है कि
ा है, जिससे
जखबर के
छिपे बहुतेरे
तताओं का
ग अदालत
वित्तीय
विवि का
आक्सीजन
तु वर्तमान
होगी कि
ल उपक्रम
साढ़े चार
ा था, जिसे
र ले आये
कायतों का
नहीं किया
अपने मूल
राजनीतिक
व्यापक
मुख्यसचिव
ता में एक
। इसी के
में पदस्थ
मला भी
र प्रतिद्वंद्वी
विरोध में
प्त बताया
कारेण पुन.
वहीं डा०
रहने की
ाम यह हो
ा आश्रम
ा रहा है।
त्तियों की
तद्वंद्विता पर
की स्मृति
इस विवि
ंती वर्ष में
ाशंका को

सहयोग से

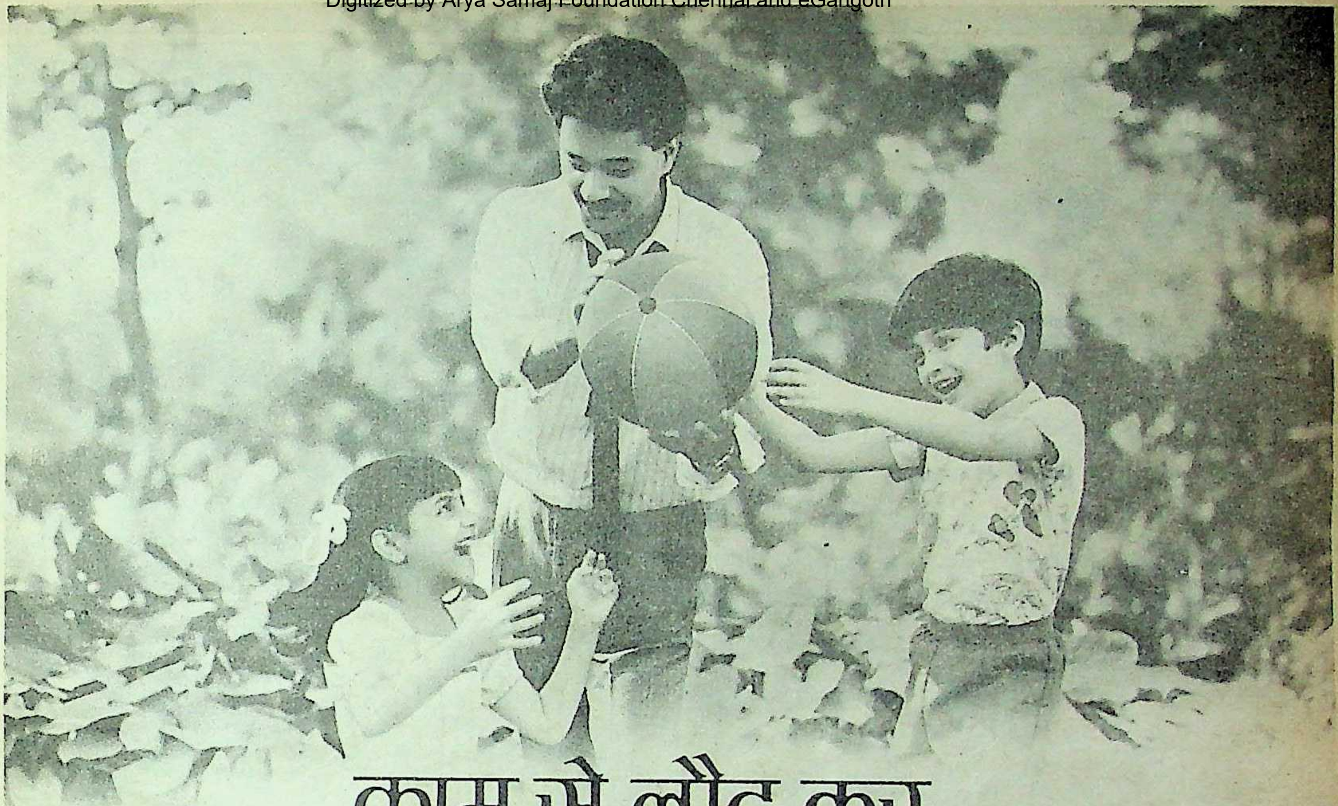

काम से लौट कर... हँसी-खुशी के पल!

ज़िन्दगी की भागदौड़, और दफ़्तर में काम का दबाव। पर शाम घर लौटने पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और आपके पति बच्चों के संग उत्साह और उमंग के साथ व्यस्त हो जाते हैं।

इसका श्रेय आपको है। क्योंकि आप दिन-भर चुस्ती और शक्ति के लिए उन्हें रोज़ हॉर्लिक्स जो देती हैं।

"हॉर्लिक्स में अत्यंत आवश्यक पोषक तत्त्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ—होते हैं जो शरीर को शक्ति, चुस्ती और तन्दुरूस्ती देते हैं। दिन-भर अच्छे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर बने रहने के लिए।"

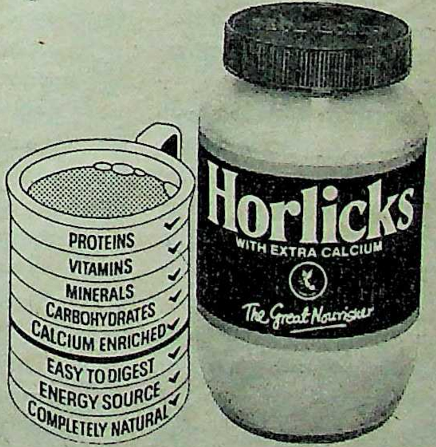
PROTEINS
VITAMINS
MINERALS
CARBOHYDRATES
CALCIUM ENRICHED
EASY TO DIGEST
ENERGY SOURCE
COMPLETELY NATURAL
Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nourisher

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6224 HIN

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट

पुलिस चौकसी की एक और मिसाल ?

आतंकवादी जून के पहले पखवाड़े में दिल्ली और पंजाब में कोई बड़ा हादसा कर सकते हैं, इस आशंका के साथ कानून-व्यवस्था के रहबरों को यह भी स्पष्ट था कि ऐसे हादसों के लिए आतंकवादी रेलवे व बस स्टेशनों तथा बाजारों के उन स्थानों को अपना निशाना बना सकते हैं जहां अकसर भीड़भाड़ रहती है। इसी कारण पूरी दिल्ली में 'रेड अलर्ट' था और पुलिस अपने समस्त अत्याधुनिक उपकरणों, हथियारों गुप्तचरों और संसाधनों के साथ चरम चौकस होने का दावा कर रही थी, लेकिन इस चौकसबंदी के बावजूद ऐन नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही बम-विस्फोट का इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया ?

हादसे के बाद खोखली सतर्कता : घटना स्थल की जांच करता एक विशेषज्ञ

कराची की तीन साल की बच्ची तो एक तिनका मात्र थी उस आंधी के लिए, जिसने १६० पौंड के एक मोटे-तगडे आदमी को २५ फुट ऊंची छत तक उछाल दिया और मांस के एक बड़े लोथड़े में तब्दील कर फर्श कर गिरा दिया। पांच घटनास्थल पर ही ढेर हो गये, चार छलनी हुए बदन की पीड़ा कुछ देर झेलने के बाद। पड़ोसी देश की मासूम बच्ची उन्हीं चारों में एक थी।

अख्तर हुसेन कराची से सपरिवार अपने कलकत्तावासी रिश्तेदारों से मिलने चले थे। साथ में उनकी बीवी सईदा बेगम, बेटी सरवरी और दो बेटे अनवर और अकबर थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अपनी प्यारी बेटी को मौत के बर्फीले हाथों के हवाले कर आधे रास्ते से ही वापस लौट जाना पड़ेगा। यह परिवार फ्रंटियर मेल से पाकिस्तान से दिल्ली और फिर नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। बाप आगे की यात्रा के लिए टिकट खरीदने गया था और मां अपने तीन बच्चों को खिला-पिला रही थी। तभी आसमान को गुंजा देनेवाला यह विस्फोट हुआ, जिसने उनकी खुशहाल जिंदगी पर दुख का पहाड़ गिरा दिया। इस परिवार की ही तरह बम के इस धमाके ने बहुत से परिवारों का जीवन तबाह कर डाला। क्षणभर पहले जो रेलवे स्टेशन आने-जानेवालों की आशा-उमंगभरी चहल-पहल से गुलजार था, क्षणभर बाद वह बिखरी-छितरी अंतड़ियों, अंग-प्रत्यंगों, मांस तथा खून के थक्कों और टूटे-फटे बक्सों-थैलों से पट गया। लहूलुहान लोगों की दर्दनाक चीखों से हवा कांप उठी। धूएं का ऐसा बगूला उठा जो स्टेशन हाल में एक मोटा लबादा और आसमान में बादल बनकर छा गया।

घटना की तीव्रता : बिहार के अगनू मुखिया अन्य ग्यारह व्यक्तियों के साथ कतार में भटिंडा का टिकट लेने के लिए खड़ा था। कुछ ही देर पहले दिल्ली आये रवि मेहता अंबाला का टिकट ले रहे थे। कलाधरंबी अपने केरल जा रहे मित्रों को 'सी आफ' करने स्टेशन पर आये थे। वे प्लेटफार्म टिकट के लिए खिडकी की ओर गये, दोस्त प्लेटफार्म के फाटक पर प्रतीक्षा करने लगे। इन तमाम लोगों की प्रतीक्षाएं उस विस्फोट ने अचानक खतम कर दीं। अब नयी प्रतीक्षाएं शुरू हुई—अस्पताल में प्रिय और आत्मीयजनों की प्रतीक्षाएं।

५००० वर्गफुट के बुकिंग हाल में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब ३०० आदमी थे—खड़े, बैठे, चलते-फिरते, पूछताछ करते, टिकट लेते या ट्रेन आने का इंतजार करते हुए। बालकनी में खड़े-खड़े अपने भाई का इंतजार कर रहे प्रेम तुलसियान

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन

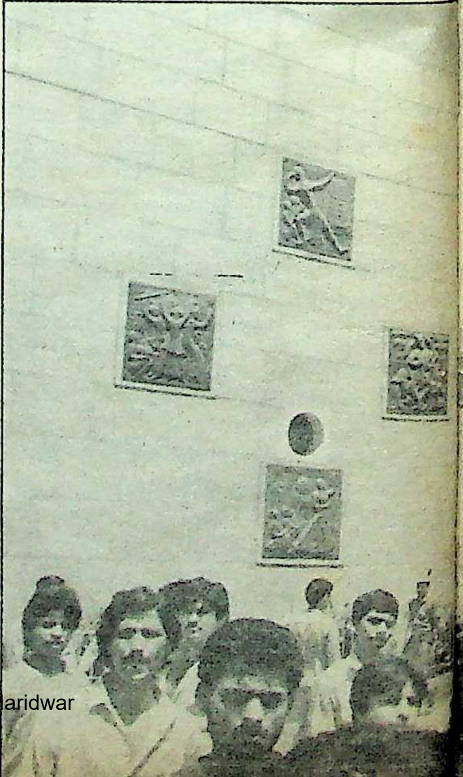

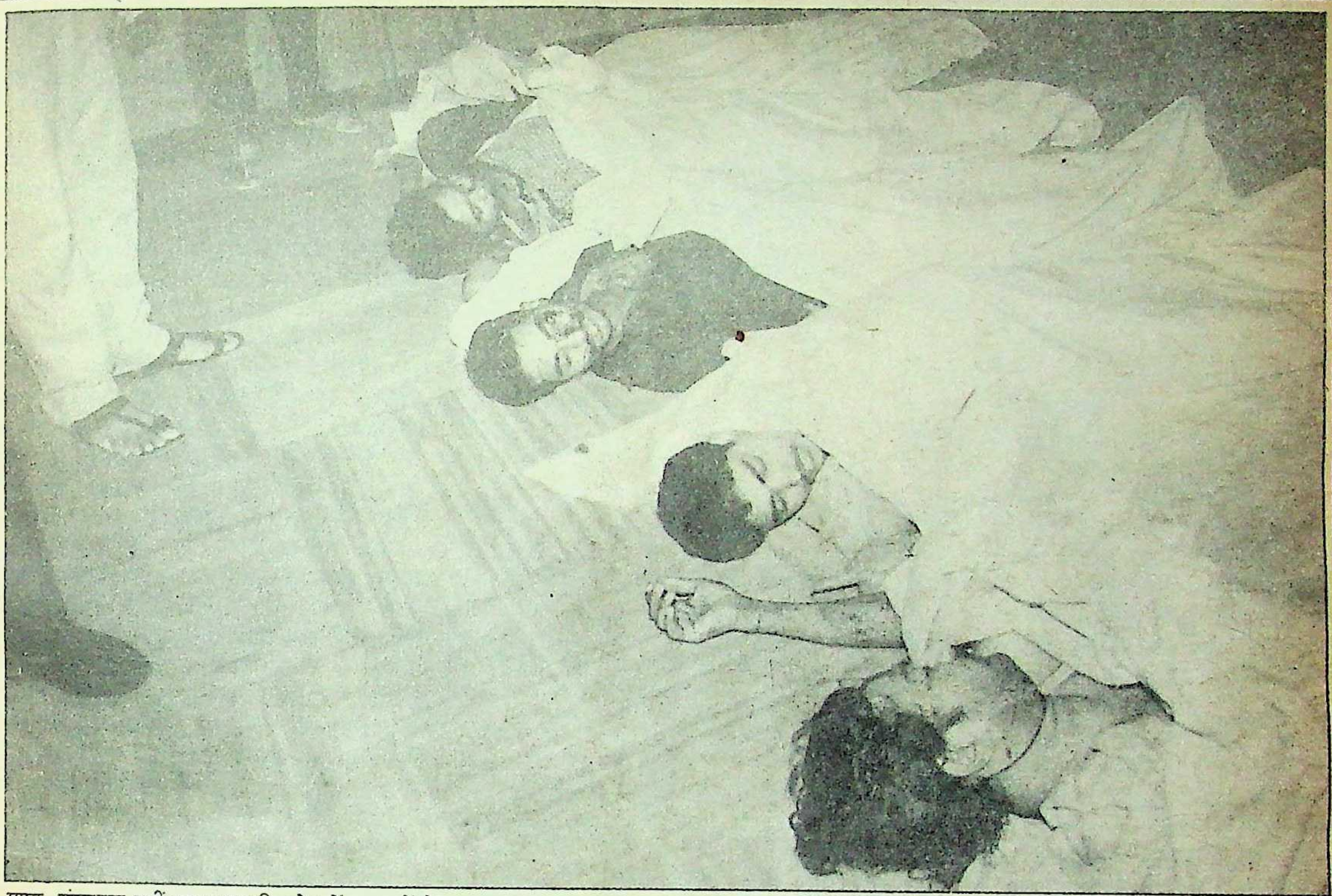

सफर मंगलमय नहीं रहा: बम-विस्फोट में हताहतों के शव

बताते हैं, "विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उससे सीधे ऊपर फेंका गया एक आदमी छत से इतने जोर से जा टकराया कि वह (छत) खून से रंग गयी। लोगों के बक्से-थैले और शरीरों के अंग पूरे हाल में बिखर-छितर गये। मर्द, औरत, बच्चे जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग चले। कई बम के छर्रों से लहूलुहान हो गिर पड़े, बाकी लोग हताहतों, छितरे अंगों और खून के थक्कों पर पांव रखते हुए बाहर निकल भागे। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि बहुतेरे लोग समझ ही नहीं पाये कि हुआ क्या? १२ जून को पूर्वाह्न १०.३५ बजे हुए विस्फोट से फर्श में १५ सेमी × २५ सेमी का गड्ढा बन गया।

अनुकरणीय सेवा: प्रथम अनुमानों के अनुसार देश की राजधानी में विस्फोट का सबसे बड़े हादसा दर्ज करनेवाला यह एक 'क्रूड बम' था जो एक बाल्टीनुमा गोल पात्र में तीन किग्रा नट-बोल्ट के अंदर रखा हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार यह बम-विस्फोट एक 'टाइमर' के जरिए किया गया। नट-बोल्ट ने तेज रफ्तारवाले घातक छर्रों का काम किया और ५० मीटर की परिधि के अंदर किसी भी आदमी या सामान को साबुत नहीं छोड़ा।

इस हृदयविदारक दृश्य ने जहां आदमी के सबसे घटिया कुकृत्य को उजागर किया, वहीं संकट में उसकी सेवा-सहायता के अनुकरणीय उदाहरण

भी पेश किये। सहृदय टैक्सी ड्राइवर और पोर्टर तत्काल निःस्वार्थ भाव से हताहतों की मदद में जुट गये। एक अधेड़ सिख अपनी टैक्सी में घायलों को लाद कर रेलवे अस्पताल पहुंचाते हुए कई बार देखा गया। "पहली खेप में मैं तीन घायलों को ले गया। उनमें से एक की बांह उड़ गयी थी। उन सबके शरीर से इतना खून बह रहा था कि मेरी गाड़ी में रक्त के थक्के जम गये। इतना खून कि...बाप रे!" उसने भरे गले से बताया। जब उसका नाम पूछा गया, तो बोला, "नाम में क्या रखा है? मेरा जो फर्ज था, वह मैंने पूरा किया। मैं कोई पुरस्कार नहीं चाहता।" उसकी तरह कइयों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी मदद की और अपनी सेवा को बिना किसी से बताये चले गये।

अस्पताल का नजारा : पूरे स्टेशन पर आदमी के दुख-दर्द में आदमी की सहज हमदर्दी और राहत-मदद का माहौल था। लेकिन अस्पताल का नजारा कुछ और था। पीड़ा से ऐंठते-छटपटाते मरीजों (विस्फोट से घायल लोगों) की चीख-कराह से दूसरों की छाती फटी जा रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भर गये थे, इस दर्दनाक नजारे से। इतने घायलों को देखने के लिए जितने डाक्टर चाहिए थे, इस दृष्टि से डाक्टरों की संख्या बहुत ही निराशाजनक थी। दुर्घटना की खबर मिलने पर अस्पताल के जूनियर डाक्टर भागे-भागे कैजुअलिटी वार्ड पहुंचे और सेवारत डाक्टरों की सहायता करने की पेशकश की, लेकिन अस्पताल के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हें यह कहकर हटा दिया कि उनकी मदद की जरूरत नहीं है। पर सचाई कुछ और ही थी। गंभीर रूप से घायल पांच में से बमुश्किल दो मरीजों के आपरेशन में ही दिन का तीसरा पहर गुजर गया। राममनोहर लोहिया अस्पताल में सभी घायलों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। कु० डौली बताती हैं, "नर्सों को कई बार सजग किया गया कि 'ड्रिप' का चलना बंद हो गया है, लेकिन वे इतनी व्यस्त और तेजी में रहती थीं कि 'ड्रिप' बदल ही नहीं पाती थीं। कुछ ऐसे भी घायल थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तीन घंटे तक नहीं देखा गया। चंडीगढ़ के गुरदीप सिंह चाहते थे कि उन्हें चंडीगढ़ के ही किसी अस्पताल में भेज दिया जाये, "भाई साहब, अस्पताल में मैं तीन घंटे तक पड़ा रहा, इसके पहले एक सुई तक नहीं लगायी गयी।"

यह भी देखा गया कि मरीजों के खून से भीगे कपड़े और बेडशीटें अर्द्धसैनिक कर्मचारी नहीं, बल्कि घायलों के अपने आदमी ही बदल रहे थे। हालात से झल्लाया हुआ एक डाक्टर आखिर बरस ही पड़ा, "हम हड़ताली डाक्टरों की सेवा-सहायता का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने खुद इसकी पेशकश की? आखिरकार, अब तक हम एक साथ, मिलजुल कर काम करते ही रहे हैं। आज सरकार की भेदभाववाली नीति के चलते, परीक्षा की इस घड़ी में वे हमारी बिरादरी से बाहर कर दिये गये। क्या यही न्याय है?"

क्षणभर पहले जो रेलवे स्टेशन आने-जानेवालों की आशा-उमंगभरी चहल-पहल से गुलजार था, क्षणभर बाद वह बिखरी-छितरी अंतड़ियों, अंग-प्रत्यंगों, मांस तथा खून के थक्कों और टूटे-फूटे बक्सों-थैलों से पट गया। लहूलुहान लोगों की दर्दनाक चीखों से हवा कांप उठी। धूएं का ऐसा बगूला उठा जो स्टेशन हाल में मोटा लबादा और आसमान में बादल बनकर छा गया।

अलबत्ता रेलवे अस्पताल में मरीजों की देखभाल और उपचार की व्यवस्था बढ़िया थी। शुरू में यहां भी कुछ गलतफहमी हुई, पर जल्दी ही दूर भी हो गयी। फिर सब ठीकठाक चलने लगा। अगनू मुखिया का हाथ 'शार्पनेल' से कट गया है। "मेरा हाथ तो गया," डबडबाई आंखों के साथ वे ड्यूटी पर लगे डाक्टर से पूछता है, "क्या मेरा हाथ काम करेगा?" ग्यारह संघातियों के साथ काम-धंधे की तलाश में घर से निकला अगनू मुखिया इस क्रूर दुर्घटना में फंस गया है। उसके ग्यारह संघांती कहां किस हालत में हैं, कौन बताये?

पुलिस की थ्योरी : बम विस्फोट से घायल आधे दर्जन लोगों [illegible] होने की शिकायतें भी दर्ज की गयी हैं। गुलशन भाई और सीएम मिश्र ने (रेलवे अस्पताल में) यह तकलीफ बतायी है। उनके दो लड़कों और पत्नी को भी 'शार्पनेल' के जख्म हैं। विस्फोट में घायल कल्याण सिंह नामक पोर्टर भी १४ जून को मर गया। पुलिस को संदेह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सामान देखते रहने के लिए कल्याण सिंह को १०० रुपए दिये थे, इसलिए इस खूनखराबे के मामले में कल्याण सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था। पुलिस की यह 'थ्योरी' न तो युक्तियुक्त दिखती है और न हादसे के चश्मदीद गवाहों की बातों से मेल खाती है। एक पोर्टर बताता है, "कल्याण और दूसरे कुलियों ने पूर्वाह्न १० बजे प्लेटफार्म-१ पर आयी मालवा एक्सप्रेस से सामान उठाया था। अपरिचित मुसाफिर ने बुकिंग खिड़की के पास सामान उतरवा लिया। मजदूरी लेने के बाद कुलियों को उस प्लेटफार्म पर जाना था, जहां कुछ देर बाद झेलम एक्सप्रेस आनेवाली थी। इसके पहले वे एक-एक बीड़ी सुलगा रहे थे...और तभी धमाके और धूएं में खो गये। कल्याण का बदन छलनी हो गया। दो दिन तक मौत से जूझ कर वह ठंडा हो गया। बाद में किसी आदमी ने जो कल्याण को हादसे की जगह के पास खड़े देख चुका था, पुलिस को बता दिया कि संभवतः वही वह 'लगेज' ले आया था, जिसमें बम रखा हुआ था।" अगर यह आंखों देखा हाल विश्वसनीय माना जाये, तो जाहिर है, कल्याण मालवा एक्सप्रेस के मुसाफिर का सामान ले आया था, न कि पंजाब से आयी किसी गाड़ी के मुसाफिर का। पुलिस की सोच यह है कि संदिग्ध आतंकवादी यह बम पंजाब से चलकर सवेरे दिल्ली पहुंचनेवाली गाड़ी से ले आया था और स्टेशन पर बम रखकर उसके फटने के पहले ही पंजाब जानेवाली ट्रेन से निकल भागा।

सुरक्षा की सचाई : ध्यान देने की बात है कि 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' की बरसी (४ जून) के आसपास आतंकवादी हादसों की संभावना की खबरें मिलने के फलस्वरूप दिल्ली पुलिस चौकस थी। उसे गुप्तचर, सशस्त्र बल तथा दूसरे सब साधन दिये गये थे, फिर भी वह अभी तक अंधेरे में तीर मारती रही है। विस्फोट की जांच के लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में १२ गुप्तचरों की एक टीम बना दी गयी है। पुलिस ने पहाड़गंज की उस दुकान को पहचान लेने का दावा भी किया है जहां से 'नट-बोल्ट' खरीदे जाने की आशंका है! पूछताछ में अब तक करीब चार दर्जन लोगों से मिले सुरागों के आधार पर संदिग्ध आतंकवादियों का हुलिया तैयार की जा चुका है। कई स्थानों पर दबिश भी डाली गयी है। लेकिन अभी तक सारे प्रयास व्यर्थ रहे हैं। दिल्ली के पुलिस प्रमुख विजय करण ने पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि अभी तक कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही।

पुलिस अपना एक नारा खासतौर से प्रचारित करती है, "आपकी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है।" लेकिन कितनी सचाई है, इस नारे में?

—विवेक शर्मा

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

कांग्रेस के मुकाबले

विपक्ष कितने पानी में

चौधरी देवीलाल ने १९ जून को हैदराबाद में दावा किया है कि विपक्षी दल अगले चुनाव में लोकसभा के ४२५ स्थानों पर विजय प्राप्त करेंगे और अगली सरकार राष्ट्रीय मोर्चे की बनेगी। देवीलाल के अनुसार जनता दल, तेलुगूदेशम, असम गण परिषद, कांग्रेस-स और द्रमुक का राष्ट्रीय मोर्चा लगभग ३७५ स्थानों पर लड़ेगा, शेष १६७ सीटें भाजपा, वामपंथी तथा अन्य दलों के हिस्से में रहेंगी। लेकिन अभी विपक्ष अपने 'गृहयुद्धों' को शांत करने, सीटों के तालमेल की समस्या से जूझने और एक चुनाव निशान तलाशने में ही लगा है, जबकि 'पंचायत राज' और 'जवाहर रोजगार योजना' के धुआंधार प्रचार के साथ राजीव गांधी ने राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के जरिये अपना आक्रामक चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस को पराजित करने का दावा पूरा हो सकेगा? विपक्ष की ताकत और चुनावी रणनीति क्या है?

विपक्षी एकता के पितामह चौधरी देवीलाल ने १३ जून को घोषणा की कि चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच 'युद्ध विराम' हो गया है। लेकिन विपक्ष के लिए इस आंशिक सुखद घोषणा का अधिकांश दुखद पहलू यह है कि अभी विपक्ष घरेलू मुजाहिदीनों से ही निपट रहा है, जबकि कांग्रेस-इ ने अपने पूरे लावलश्कर के साथ उस पर धावा बोल दिया है। लाभ-हानि की बात दूसरी है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव-प्रचार करने और चुनाव-प्रसाद बांटने की पहल करने में बाजी मार ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी स्वयं राज्यों के सघन दौरे कर रहे हैं। जनसभाओं में जोर लगाकर विपक्ष को कोस रहे हैं, जिसे टीवी पर दरियादिली के साथ दर्शकों के सामने हर रोज परोसा जा रहा है। प्रदेश इंका अध्यक्षों और राज्यों के प्रभारी महासचिवों को कह दिया गया है कि वे चुनाव में 'उम्मीदवार नहीं होंगे। चुनाव लड़ना हो, तो पार्टी-पद का मुकुट उतार कर रख दें। ५० से ज्यादा प्रेक्षकों को विभिन्न राज्यों में रवाना कर दिया गया है—यह पता लगाने के लिए कि पार्टी का चुनाव-भविष्य क्या है। प्रेक्षकों के अतिरिक्त जासूसी विभाग का भी चुनावी-आकलन के लिए 'सदुपयोग' किया जा रहा है। 'जवाहर रोजगार योजना' के कोष का वितरण करने में कर्ण की दानशीलता भी फीकी पड़ रही है। पंचायत राज से गांवों में कैसे रामराज्य के कल्ले फूटेंगे—यह बताने के लिए पार्टी इकाइयों को अखंड कीर्तन में लगा दिया गया है।

स्थायी सरकार का सवाल: कांग्रेस की इस व्यूहरचना को पृष्ठभूमि में रखकर अब यह देखने का वक्त आ गया है कि क्या विपक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ दल को मैदान चटाने की स्थिति में है? कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है कि तीन-तेरह दलों को जोड़-गांठ कर यदि विपक्ष बहुमत हासिल कर भी लेता है, तो वह स्थायी सरकार नहीं दे सकता। हाल में कर्नाटक की जनता सरकार के असामयिक निधन ने कांग्रेस को अपने आरोप को रेखांकित करने का मौका और दे दिया है। ऐसी हालत में क्या विपक्ष जनता को आश्वस्त करने की स्थिति में है कि यदि उसे जनता ने जिताया, तो उसकी सरकार का हश्र वैसा नहीं होगा, जैसा १९७९ में जनता पार्टी की सरकार का हुआ था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पीछे मुड़कर अतीत की ओर लौटना होगा। पिछले वर्ष जून के मध्य में मरियल और दिशाहीन विपक्ष की धारा को तीव्र वेग और अपेक्षित दिशा तब मिली थी, जब इलाहाबाद का लोकसभाई उपचुनाव हुआ था। दायें-बायें का भेद भुलाकर विपक्ष ने इस उपचुनाव का किला फतह किया था और जनता को यह आभास दिया था कि विपक्ष कांग्रेस का सशक्त विकल्प दे सकता है और विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके नवोदित निर्विवाद नेता हैं। आभास पूर्ण सत्य नहीं होता, लेकिन गाजे-बाजे

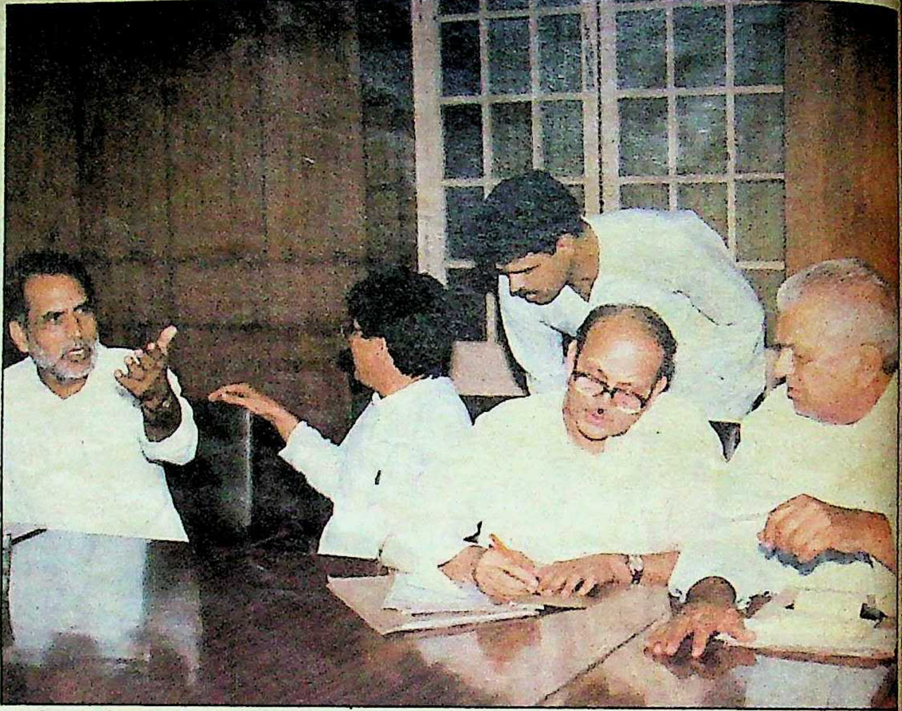

युद्ध के बाद विराम: दिल्ली में १४ जून की बैठक में जनता दल के नेता

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

हम तैयार हैं: (बायें से) राष्ट्रीय मोर्चे की बैठक के बाद रामाराव, वीपी सिंह, करुणानिधि, देवीलाल, बीजू पटनायक

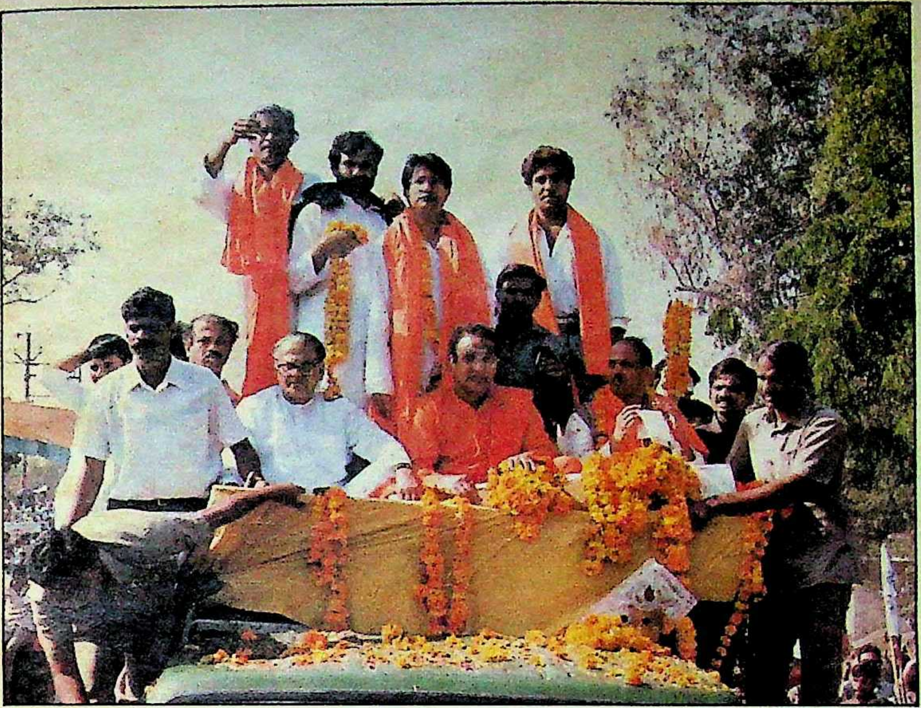

विजय के लिए आश्वस्त : विपक्षी नेता एक रैली में

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

विपक्षी एकता के पितामह : देवीलाल

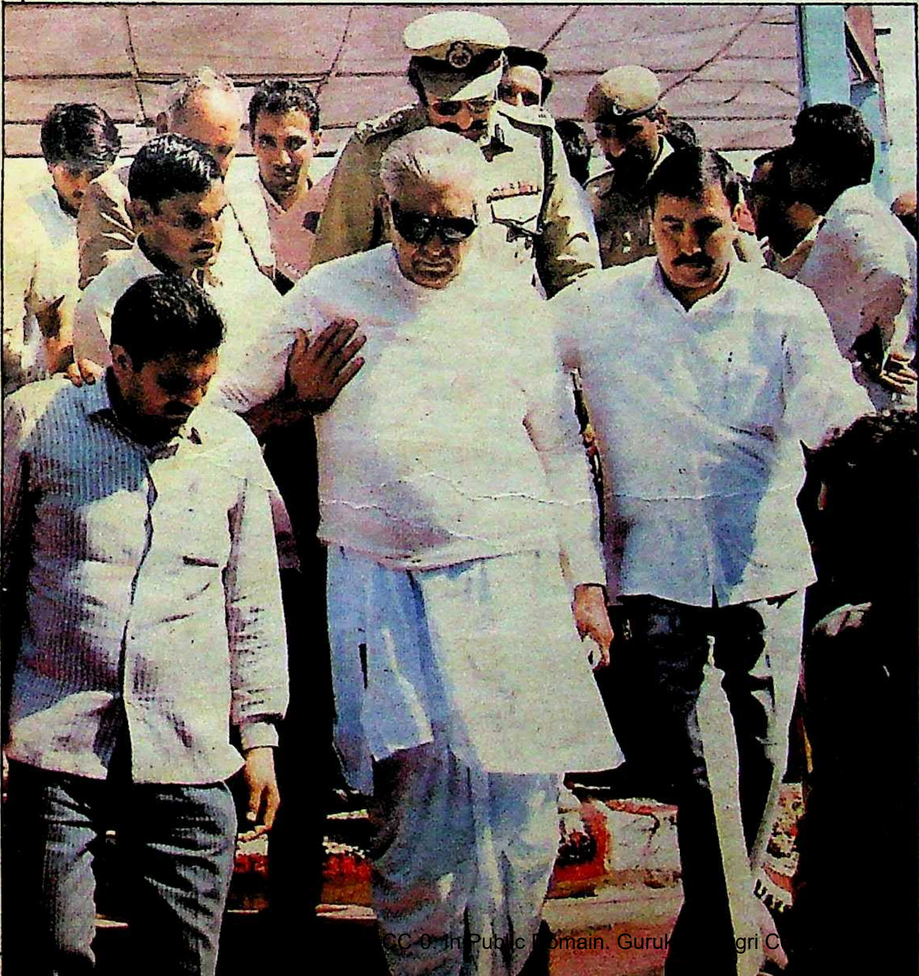

के महाभारतीय माहौल में यह पता लगाना संभव भी नहीं कि अश्वत्थामा हत हुआ है या उसी नाम का हाथी मारा गया है। हकीकत की कड़वाहट बाद में सामने आती है। इलाहाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस का मान-मर्दन करने के लिए विपक्ष अनायास एक हुआ था। यह पता था कि इस जीत से न तत्काल कांग्रेस का पतन होने जा रहा है और न किसी को तुरंत प्रधानमंत्री का पद मिलनेवाला है। इसलिए कांग्रेस-इ और राजीव गांधी के विकल्प के लिए उस उपचुनाव में विपक्षी राजनीति की जो कोख हरी-भरी हुई थी, उसकी वल्दियत का झगड़ा बाद में सामने आया। सबसे भीषण युद्ध चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह में शुरू हुआ, जिसकी चरम परिणति उस समय सामने आयी, जब वीपी सिंह पर घातक टिप्पणी का जेपी का पत्र सामने आया और बिहार जनता दल के मुखिया और चंद्रशेखर के आश्रित रघुनाथ झा की कुरसी छीन कर वीपी सिंह ने रामसुंदर दास के नीचे खिसका दी। इससे पहले कि चित-पट होने की नौबत आती, चौधरी देवीलाल ने अपने दबंग हस्तक्षेप से बात सुधार ली और १३ जून को 'युद्ध विराम' की घोषणा कर दी।

नयी व्यवस्था : नयी व्यवस्था के तहत जनता दल के सांगठनिक मसलों से निपटने के लिए आरिफ मोहम्मद खान के संयोजकत्व में सात सदस्यीय तदर्थ समिति बना दी गयी है, जिसे ४५ दिन के अल्पकाल में सांगठनिक निर्माण की समस्याओं का समाधान तलाशना है। दूसरी ओर, चंद्रशेखर को उच्चाधिकार प्राप्त सात सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति का सातवां सवार स्वीकार कर लिया गया है। चंद्रशेखर निरंतर यह रट तो लगाये हुए थे कि उन्हें वीपी सिंह का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं, साथ ही यह भी गिला करते रहते थे कि वे जनता दल की निर्णय प्रक्रिया के हिस्से नहीं। अब उनकी टिकट-वितरण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी होगी जो काफी महत्वपूर्ण है। नेतृत्व के सवाल पर उम्मीद है कि अब वे चुनाव तक सार्वजनिक बयानबाजी से बाज आयेंगे।

घर के कलह को सड़कों पर आने से रोकने के लिए विपक्ष के चौधरी देवीलाल ने जो 'युद्ध विराम' करवाया है, उससे जनता को १९७७ की जनता पार्टी की जो त्रासदी याद आ रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इस युद्ध विराम के बाद रघुनाथ झा पटना में १९ जून को सम्मेलन करके राज्य में जनता दल के बंटवारे की जो नींव रखने वाले थे, वह टल गयी। यद्यपि उत्तर प्रदेश में युद्ध विराम के बाद भी चंद्रशेखर-समर्थक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने 'संजय सिंह जैसे कतल के आरोपी' को प्रदेश जनता दल के प्रधान सचिव के पद से हटाने की मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन चंद्रशेखर के चुप्पी साध लेने के बाद यह जेहाद ज्यादा खतरनाक नहीं है। फिर राजमंगल पांडेय की अध्यक्षता में बनी अनुशासन समिति को भी सख्त कदम उठाने की हिदायतें दे दी गयी हैं। इस पर चौधरी देवीलाल की यह हरियाणवी धमकी भी अनुशासन स्थापित करने में भूमिका निभायेगी कि

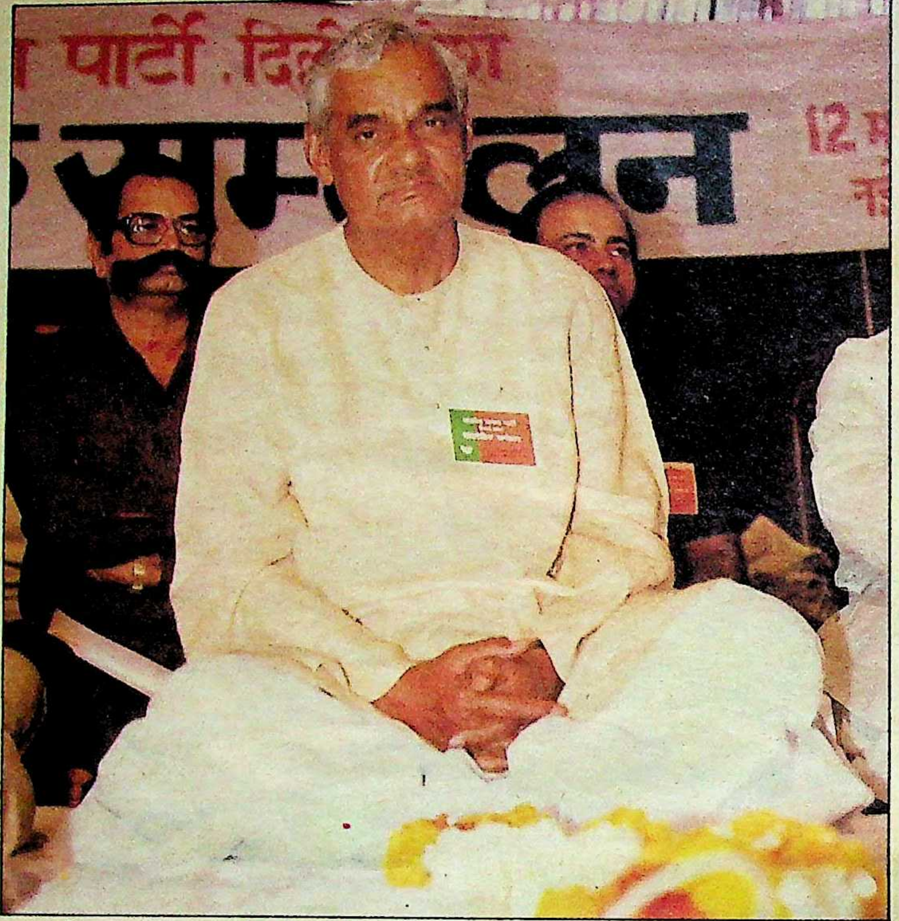

भाजपा के प्रधानमंत्री : अटल बिहारी वाजपेयी

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

> विलय की परिणति जनता दल के रूप में है, तो साझा के तहत राष्ट्रीय मोर्चा आता है और तालमेल के अंतर्गत भाजपा और वामपंथी दलों को लिया गया है।

> इससे सिद्ध है कि अधिक मत विपक्ष के पास हैं और ये मत यदि विभाजित नहीं होते हैं, तो विपक्ष को बहुमत में आने से कोई नहीं रोक सकता।

विपक्ष की एकता को भंग करनेवाले कुछ निकल गये हैं और कुछ निकाल दिये जायेंगे। जनता दल के कुछ लोग इस कलह को एकता के निर्माण की प्रसव वेदना का हिस्सा मानते हैं और इससे हताश नहीं हैं। जनता दल सांसद जयपाल रेड्डी का मानना है, "अच्छा है इस बार १९७९ (फूट) पहले हो रहा है, १९७७ बाद में आयेगा।" एक सांसद ने इसे सत्ता में भागीदारी के लिए अनिवार्य रस्साकशी की संज्ञा देते हुए मजाक किया, "हमारे यहां दशरथ (वीपी सिंह) एक हैं और कैकेइयां अनेक।" जिसको महत्व नहीं मिला, वही कोपभवन में जाकर बैठ जाता है। शायद इसी कोप से निजात पाने के लिए वीपी सिंह ने दर्जनों समितियां बना दी हैं।

महत्वपूर्ण घटना : एकता बनाये रखने के लिए जनता दल जो प्रयत्न कर रहा है, यदि वे सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से मतदाता पर अच्छा असर पड़ेगा। जनता दल नेता और चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन का दावा है कि जनता पार्टी के छिन्न-भिन्न होने के लंबे अंतराल के बाद जनता दल का गठन एक सर्वथा महत्वपूर्ण घटना है। उनके अनुसार १९७७ के बाद पहली बार एक बड़ा विपक्षी दल बना है, जिसमें मध्यमार्गी पार्टियां शामिल हुई हैं। तब की जनता पार्टी और अब के जनता दल में वे दो स्पष्ट अंतर मानते हैं। पहला, जनता पार्टी जल्दबाजी में बनी थी। उसे सत्तारूढ़ होने से पहले विचार-मंथन कर नीति-निर्माण करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। नतीजतन, नीतियों, कार्यक्रमों की निर्माण प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो वह उसके विघटन का कारण बन गयी। जनता दल को नीति-कार्यक्रम बनाने का पर्याप्त अवसर मिला है, इसलिए इसे बाद के आशंकित अंतर्कलह से बचायेगा। दूसरा, उस समय दक्षिणपंथी जनसंघ जनता पार्टी का घटक था, आज भाजपा नहीं है।" इसके चलते वैचारिक समानता की नींव अधिक गहरी हुई है जो जनता दल को अधिक भरोसे योग्य और टिकाऊ पार्टी बनाती है।"

कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता दल अकेला नहीं। वह राष्ट्रीय मोर्चे का हिस्सा है, जिसमें तेलुगूदेशम, द्रमुक और असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य दलों के बीच मतभेद की कम गुंजाइश है। मोर्चे के अध्यक्ष एनटी रामाराव हैं, तो उसके संयोजक वीपी सिंह। इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। फिर क्षेत्रीय दल जहां सत्तारूढ़ (आंध्र, असम और तमिलनाडु) हैं, वहां उनका टिकट वितरण [illegible] जो सबको स्वीकार्य है।

१८ जून की घोषणा के अनुसार मोर्चा लोकसभा की ५४३ सीटों में से ३७५ पर चुनाव लड़ेगा। लोकसभा की २१४ सीटें हिंदीभाषी क्षेत्रों में हैं, जहां निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जनता दल के नेता शरद यादव के अनुसार त्रिसूत्री रणनीति अपनायी गयी : विलय, साझा और तालमेल। विलय की परिणति जनता दल के रूप में है, तो साझा के तहत राष्ट्रीय मोर्चा आता है और तालमेल के अंतर्गत भाजपा और वामपंथी दलों को लिया गया है। इन तीनों रणनीतियों की सफल क्रियान्विति के बाद कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष एक भीमकाय विकल्प के रूप में सामने आता है। इसका परिणाम होगा, कांग्रेस के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार को उतारना और यही रणनीति कांग्रेस के लिए जानलेवा है। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी डाले गये मतों में से अधिक-से-अधिक ४० प्रतिशत मत प्राप्त करके सत्ता में आती रही है। १९८४ की असामान्य परिस्थिति में भी उसे ४८ प्रतिशत ही मत प्राप्त हुए थे। इससे सिद्ध है कि अधिक मत विपक्ष के पास हैं और ये मत यदि विभाजित नहीं होते हैं, तो विपक्ष को बहुमत में आने से कोई नहीं रोक सकता।

यक्ष प्रश्न : लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि क्या

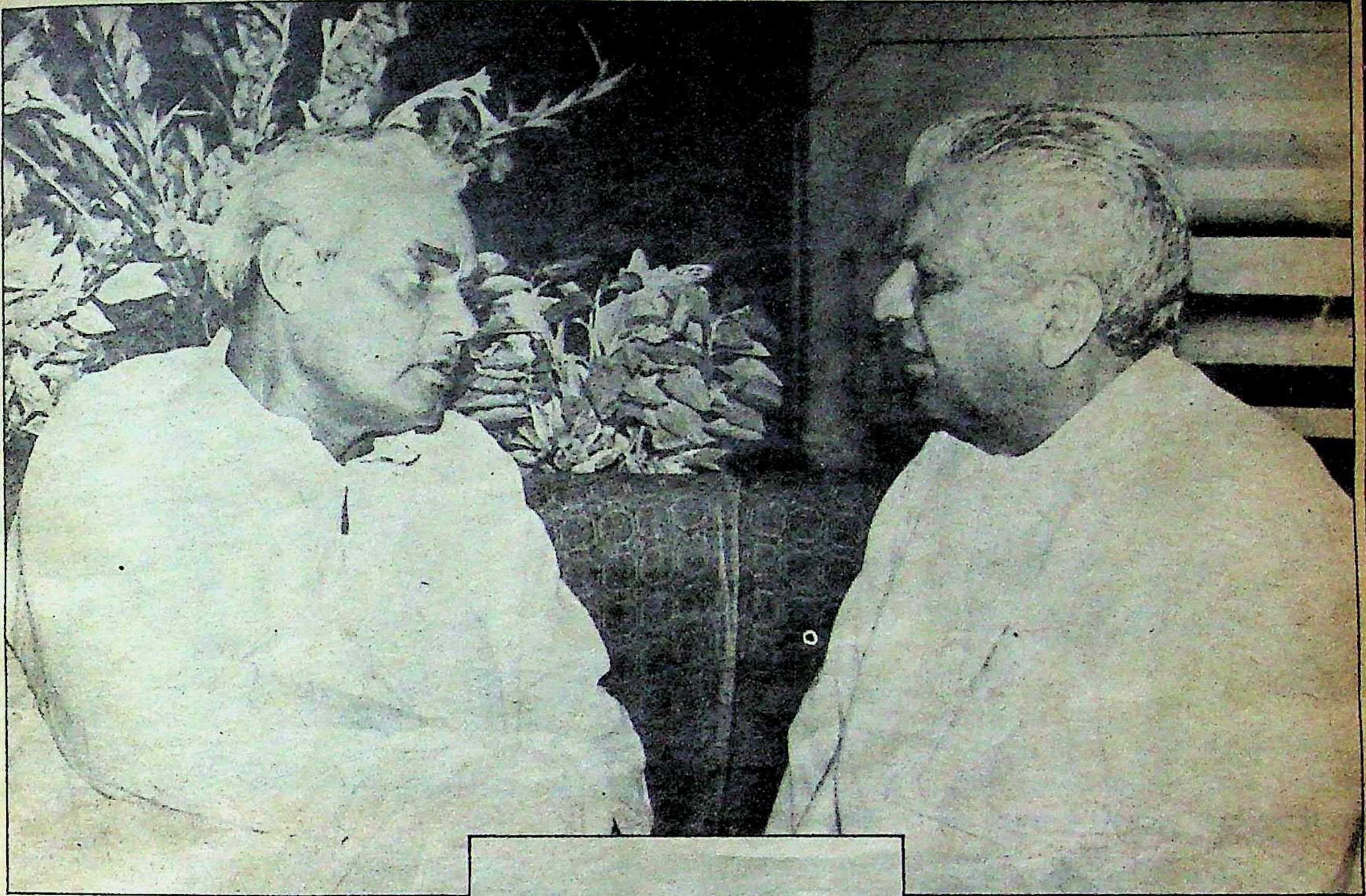

तालमेल की संभावना: वाजपेयी और देवीलाल

घर के कलह को सड़कों पर आने से रोकने के लिए विपक्ष के चौधरी देवीलाल ने जो 'युद्ध विराम' करवाया है, उससे जनता को १९७७ की जनता पार्टी की जो त्रासदी याद आ रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इस युद्ध विराम के बाद रघुनाथ झा पटना में १९ जून को सम्मेलन करके राज्य में जनता दल के बंटवारे की जो नींव रखनेवाले थे, वह टल गयी। यद्यपि उत्तर प्रदेश में युद्ध विराम के बाद भी चंद्रशेखर-समर्थक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने 'संजय सिंह जैसे कतल के आरोपी' को प्रदेश जनता दल के प्रधान सचिव के पद से हटाने की मुहिम छेड़ रखी है।

ऐसा हो सकता है? यह मान लेते हैं कि जनता दल कुल मिलाकर एक रहेगा और राष्ट्रीय मोर्चे से भी तादात्म्य कायम रहेगा, लेकिन भाजपा और वामपंथी दलों से भी क्या ऐसी पटरी बैठ सकेगी? सैद्धांतिक स्तर पर यह तय है कि ऐसा संभव नहीं है। भाजपा ने जून के दूसरे सप्ताह में पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है। वह अपना अस्तित्व बरकरार रखेगी और संविधान की धारा ३७० (कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी) तथा अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करवाना चाहती है और वह अयोध्या के विवादास्पद धर्मस्थल को हिंदुओं को सौंपने की पक्षधर है। उसने प्रधानमंत्री-पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। यदि प्रधानमंत्री-पद की दावेदारी को मात्र औपचारिकता भी मान लिया जाये, तो भी बाकी बातें जनता दल के सैद्धांतिक दायरे से बाहर पड़ती हैं। फिर कांग्रेस ने जनता दल के साथ भाजपा के संभावित तालमेल का उदाहरण पेश करके जनता दल पर सत्ता के लिए सांप्रदायिक ताकतों से गठजोड़ करने का आरोप लगाने की मुहिम तेज कर दी है, ताकि रूठे हुए मुस्लिम मतदाताओं को इसी बहाने राजी किया जा सके। लेकिन केरल में मुस्लिम लीग से तालमेल और मिजोरम के चुनाव घोषणा[illegible] में ईसाइयत को प्राधान्य देने के उदाहरण से कांग्रेस पर सांप्रदायिकता का जवाबी आरोप लगाने का मसाला जनता दल के पास है। कुछ भी हो, स्पष्ट है कि जनता दल हर हाल में भाजपा से तालमेल करेगा। यह बात भी तय है कि यह तालमेल वीपी सिंह के 'स्वाभाविक सहयोगी' वामपंथियों को गवारा नहीं होगा। लेकिन वामपंथ के पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक सीमित प्रभाव-क्षेत्र को देखते हुए जनता दल कदापि भाजपा को नहीं छोड़ेगा। इसका कारण यह है कि दोनों के हित सीधे-सीधे उस प्रभावशाली हिंदीभाषी क्षेत्र से जुड़े हैं जो सदैव से सत्ता का निर्णायक रहा है।

लोकसभा की २१४ सीटों—उप्र ८५, बिहार ५४, मप्र ४०, राजस्थान २५, हरियाणा १०, इसी क्षेत्र में हैं। इसलिए जनता दल के लिए आवश्यक है कि इनमें से अधिकाधिक सीटें जीत कर राष्ट्रीय मोर्चे का सबसे बड़ा घटक बने और साझा सरकार के नेतृत्व की दावेदारी पेश कर सके।

भाजपा का भी यही प्रभाव क्षेत्र है और वह भी अधिकाधिक सीटें हथियाने को आतुर है। यद्यपि इस समय उसके दो ही लोकसभा सदस्य हैं, किंतु भाजपा के अधिकाधिक सीटों के दावे के कुछ प्रमुख कारण बताये जाते हैं। एक, हाल के उप्र के स्थानीय निकायों के चुनावों में मिली सफलता ने उसकी

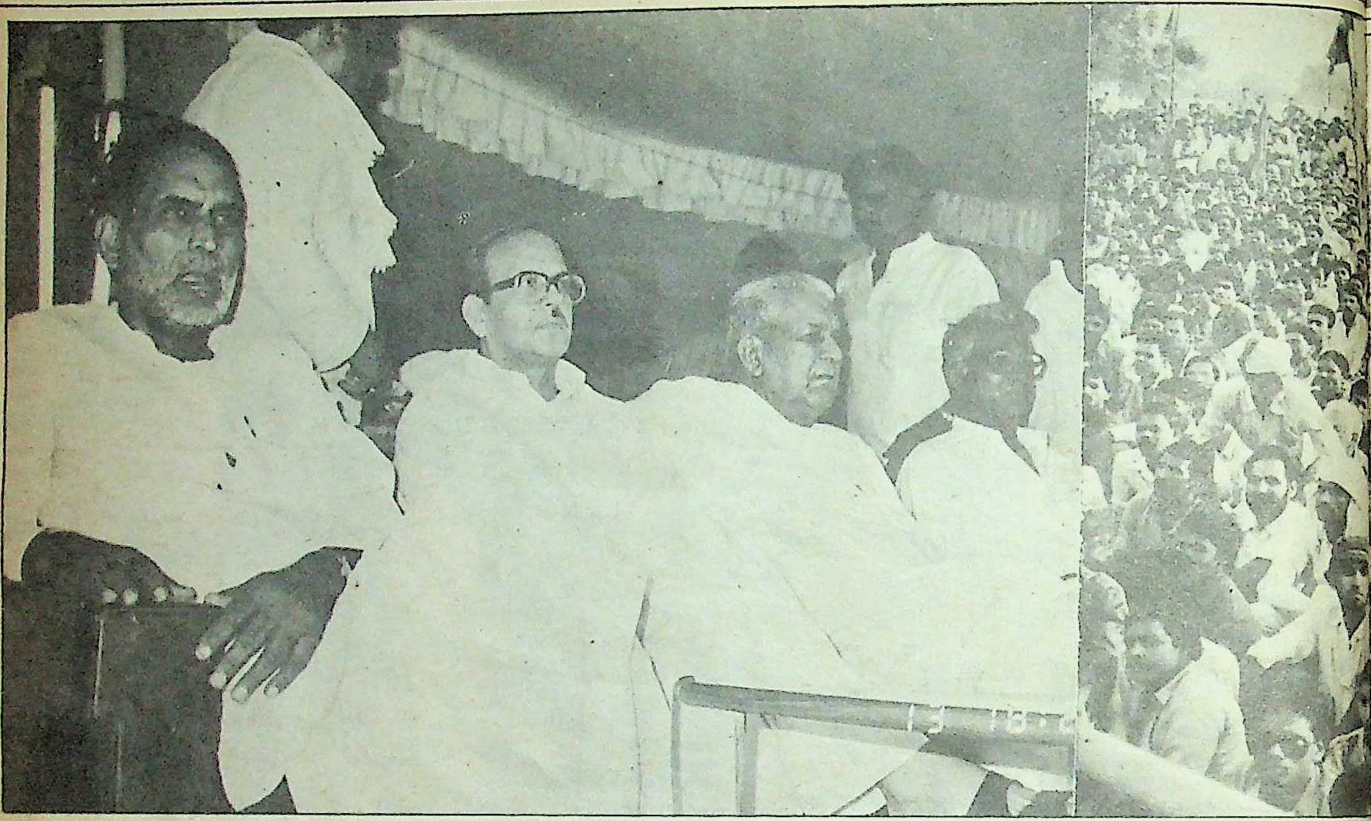

'युद्ध विराम' के बाद: फरीदाबाद में चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवीलाल एक जनसभा में

यह मान लेते हैं कि जनता दल कुल मिलाकर एक रहेगा और राष्ट्रीय मोर्चे से भी तादात्म्य कायम रहेगा, लेकिन भाजपा और वामपंथी दलों से भी क्या ऐसी पटरी बैठ सकेगी? सैद्धांतिक स्तर पर यह तय है कि ऐसा संभव नहीं है। भाजपा ने जून के दूसरे सप्ताह में पालमपुर में अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है। वह अपना अस्तित्व बरकरार रखेगी और संविधान की धारा ३७० (कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी) तथा अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करवाना चाहती है और वह अयोध्या के विवादास्पद धर्मस्थल को हिंदुओं को सौंपने की पक्षधर है।

हौसला अफजाई की है। दो, वामपंथ के अलावा भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने बकौल पार्टी अध्यक्ष आडवाणी, "शिखर वार्ताएं न कर जनसंघर्ष और जनसंपर्क द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी किया है और चुनावी तैयारी भी।" लेकिन वह अपने दम पर लड़ने और कांग्रेस की जीत के आसार बढ़ाने की मनःस्थिति में नहीं है, इसलिए वह तालमेल की इच्छुक है।

शुभ संकेत : इस दिशा में दो शुभ संकेत हैं। एक, तालमेल की महत्ता समझते हुए दोनों पार्टियों ने पुराने गिले-शिकवे भुला परस्पर बातचीत का शुभारंभ कर दिया है। दूसरे, वार्ता की कमान जनता दल की ओर से हरियाणा में भाजपा के साथ साझा सरकार चलानेवाले मुख्यमंत्री देवीलाल के हाथ में है। भाजपा का नेतृत्व अपेक्षाकृत लचीले और व्यवहारकुशल अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं। यद्यपि सूरजकुंड (हरियाणा) में दोनों के मध्य हुई दो दिवसीय लंबी बातचीत को आधिकारिक सूत्र 'प्रारंभिक' बताते हैं, किंतु जानकार सूत्रों का दावा है कि गाड़ी न सिर्फ पटरी पर है, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि जनता दल ने प्रारंभ में कहा था कि उप्र और बिहार के बारे में वह तालमेल की बात बाद में और अलग से करेगा। इस प्रस्ताव का मुख्य कारण यह था कि तीन राज्यों—मप्र, हिमाचल और दिल्ली—में जनता दल को भाजपा का प्रभुत्व स्वीकार्य है, किंतु अपने प्रभाव क्षेत्रों खासकर—उप्र, बिहार में वह नाममात्र की सीटें भाजपा को देना चाहता है। इसलिए भाजपा टुकड़े-टुकड़े में बातचीत के लिए राजी नहीं हुई। मौके की नजाकत को समझते हुए जनता दल को झुकना पड़ा।

विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि भाजपा ने प्रारंभ में २०० सीटों की दावेदारी पेश की थी। कदाचित इसका आधार यह रहा कि १९७७ के चुनाव में जनसंघ घटक के हिस्से में लगभग ९५ सीटें आयी थीं। जाहिर है कि भाजपा ने अपने मोलभाव की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ही इतनी अधिक सीटों की मांग प्रस्तुत की। इस पर मधुलिमये बोले, "भाजपाई अपने हिंदू कार्ड और रामजन्मभूमि विवाद भुनाने की आशा में हवा में उड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि इस लोकसभा में उनकी मात्र दो सीटें हैं, जबकि १९५२ में भी ३ थीं। इनका कुल वोट आज ८ प्रतिशत से भी कम है, जबकि १९६६ में ९.४ प्रतिशत था। आगामी चुनाव में भी कोई चमत्कार नहीं होनेवाला।"

लेकिन जैसा कि भाजपा अकेले मैदान में उतरने के नुकसान जानती है, इसलिए वह हर हाल जनता दल से तालमेल की इच्छुक है। भाकपा के सचिव एम फारूकी का तो मानना है कि भाजपा ८० सीटों के लिए मान जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनता दल ने महाराष्ट्र में भाजपा से तालमेल करने से इनकार कर दिया है। तर्क यह दिया गया है कि उसने शिवसेना जैसे शुद्ध सांप्रदायिक संगठन से समझौता किया है जो जनता दल को

पिछले जून के बाद विपक्ष के बढ़ते प्रभाव को पिछले दो-तीन महीनों में कांग्रेस ने आक्रामक अभियान चलाकर धूमिल किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने संगठन और कार्यक्रमों की घोषणा के स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। केंद्र और महत्वपूर्ण हिंदी क्षेत्रों में कांग्रेस के पास सत्ता-बल है, तो विपक्ष के पास भी हरियाणा, तमिलनाडु, असम, आंध्र, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस ने अपनी कितनी ही स्थिति सुधारी हो, विपक्ष भी कम पानी में नहीं है।

स्वीकार्य नहीं। असलियत यह है कि महाराष्ट्र में शरद जोशी के शेतकारी संघटना के साथ वीपी सिंह का तालमेल हो गया है, शरद जोशी का किसानों पर प्रभाव है, इसलिए यदि भाजपा शिवसेना से समझौता करके शहरी क्षेत्र में कांग्रेस से सशक्त टक्कर लेगी, तो जनता दल शेतकारी संघटना के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोहा लेगा। वहा दोनों के हितों में ज्यादा टकराव नहीं है।

इस प्रकार हिंदी क्षेत्रों में कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए उसने भाजपा से तालमेल का मार्ग प्रशस्त करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लेकिन अब सवाल उठता है, वामपंथियों के साथ तालमेल का। मात्र शिवसेना से दूर रहने से ही वामपंथी जनता दल से तालमेल करने के लिए राजी नहीं होना चाहते। उनको सबसे ज्यादा चिढ़ भाजपा से है। ईएमएस नंबूदिरीपाद कहते हैं, "अव्वल तो जनता दल और भाजपा में तालमेल की संभावना कम है। और हो भी गया, तो वह कारगर और टिकाऊ नहीं होगा।" हर हाल में इस तालमेल में टंगड़ी लगाने वाले इस मार्क्सवादी नेता की वही दलील है कि भाजपा से तालमेल करने पर जनता दल पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगेगा, जिससे अल्पसंख्यक मतदाता बिदक कर कांग्रेसी खेमे में चले जायेंगे।

दिलचस्प तथ्य : दिलचस्प तथ्य यह है कि लगभग साढ़े ६ करोड़ अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने-पटाने में इस समय पक्ष-विपक्ष दोनों जुटे हुए हैं, क्योंकि यह समुदाय चुनाव परिणामों में महती

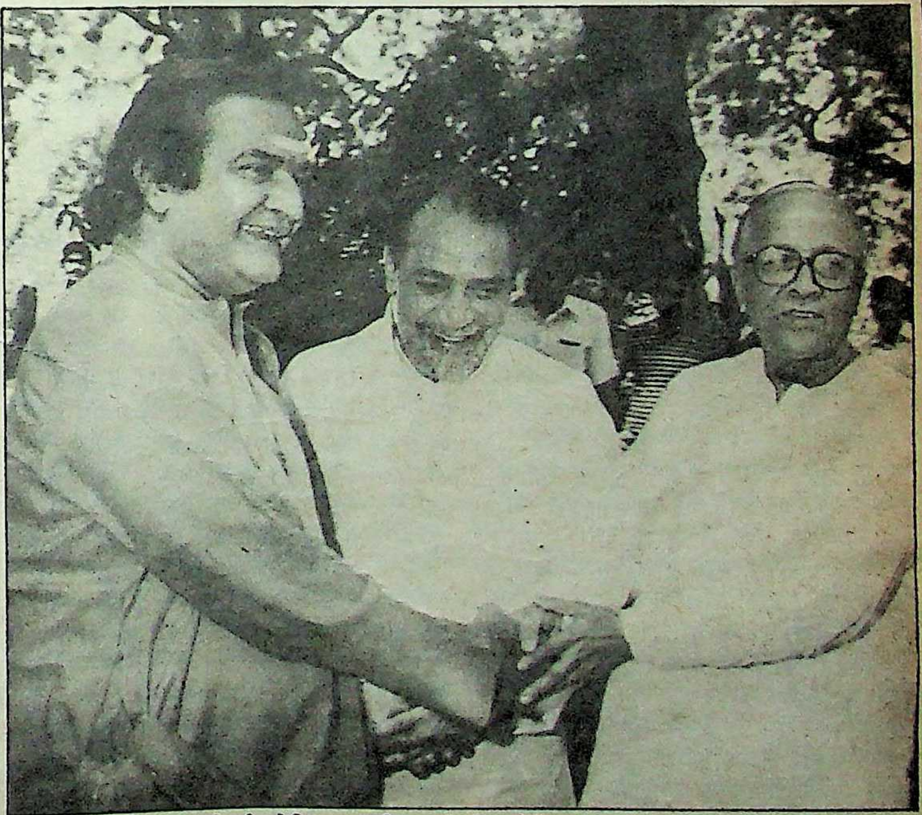

वामपंथियों से हाथ मिलाने की कोशिश : एनटीआर, [illegible], ज्योति बसु

साक्षात्कार : अटल बिहारी वाजपेयी,

'सत्ता-परिवर्तन निश्चित है'

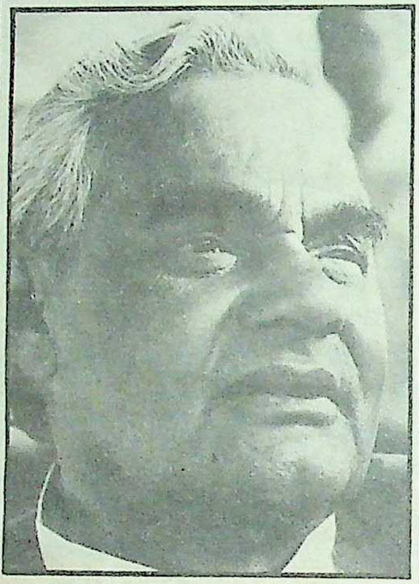

आज किसी भी दल के लिए राजीव गांधी का सीधे-सीधे समर्थन करना आत्महत्या के बराबर होगा।

माया: *जनता दल और भाजपा में आपसी तालमेल की कितनी संभावना है?*

वाजपेयी: पचास प्रतिशत।

माया: *आप किन कारणों से मात्र पचास प्रतिशत संभावना देखते हैं?*

वाजपेयी: सीटों का बंटवारा बड़ा टेढ़ा मामला है। टिकट बांटने में एक ही दल में विघटन हो जाता है। १९७७ में जनता पार्टी के विघटन की प्रक्रिया टिकट बांटने के प्रश्न को लेकर हुई थी, लेकिन अगर कांग्रेस को हराने के लक्ष्य को सभी दल सर्वोपरि मानते हैं, तो जनता के दबाव में आकर दलों को समझौता करना पड़ सकता है।

माया: *क्या भाजपा जम्मू-कश्मीर को संविधान की धारा-३७० के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का विरोध करके, अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करने की मांग और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उभारकर कांग्रेस को हरा चारा नहीं पेश कर रही है?*

वाजपेयी: इन प्रश्नों पर तो हम कांग्रेस से दो-दो हाथ कर रहे हैं। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत संविधान की धारा-३७० को बरकरार रखना चाहती है, किंतु हम नहीं। वह अल्पसंख्यक आयोग को बनाये रखना चाहती है, हम उसे समाप्त करने की मांग करते हैं।

माया: *क्या आपकी रणनीति अंततः हिंदू 'कार्ड' खेलने की है?*

वाजपेयी: हमारी रणनीति राजीव गांधी को हिंदू कार्ड नहीं खेलने देने की है। सारी पेशबंदी इसलिए है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर ऐन चुनाव-पूर्व कांग्रेस कोई ऐसी चाल न चल पाये, जिससे कि हिंदुओं को बहलाने-फुसलाने में वह सफल हो जाये।

माया: *वामपंथी जनता दल और भाजपा के मध्य तालमेल का इतना प्रबल विरोध क्यों कर रहे हैं?*

वाजपेयी: यदि वे ऐसा अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण कर रहे हैं, तो मैं कुछ सीमा तक उसे समझ सकता हूं। अंतरराष्ट्रीय दबाव से मेरा मतलब यह है कि विदेशों की कम्युनिस्ट पार्टियां उनसे कह रही हों कि विदेशों की दृष्टि से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाये रखना सबसे लाभदायक हैं। इसलिए वे उन्हें हटाने की किसी मुहिम में शामिल न हों, किंतु आज किसी भी दल के लिए राजीव गांधी का सीधे-सीधे समर्थन करना आत्महत्या के बराबर होगा। इसलिए एक रणनीति यह हो सकती है कि ऐसे मुद्दे खड़े करो, जिनसे कि राजीव गांधी के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा न बनने पाये। शायद वे सांप्रदायिकता का सवाल इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि केरल और पश्चिम बंगाल के बाहर अगर वे मुस्लिम समर्थन थोड़ा-बहुत जुटाने में सफल हो जायें, तो उन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं। अन्यथा उनके लिए सीटें जीतना बहुत कठिन है।

माया: *जनता दल और भाजपा के तालमेल का मुस्लिम मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?*

वाजपेयी: यदि मतदाता कांग्रेस को हराना चाहते हैं, तो वे इस तालमेल से बहुत खुश होंगे और यह जानकर कि कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है, वे कांग्रेस को हरायेंगे।

माया: *जैसाकि आपने पहले कहा है कि टिकटों का बंटवारा बड़ा टेढ़ा मामला है, तो टिकट न पानेवालों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विरोध से आप कैसे निपटेंगे?*

वाजपेयी: अनुशासन भंग करके जो उम्मीदवार खड़े होंगे, वे पराजित होंगे। यदि पैसे के बल पर या जाति के जोर पर ऐसे कुछ उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, तो उन्हें हराने के लिए हम विशेष जोर देंगे। ऐसे उम्मीदवार जीतकर कांग्रेस से मिल जायेंगे, यह हम मतदाताओं को बतायेंगे। जो व्यक्ति अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं रहा, उसकी मतदाताओं के प्रति कैसे निष्ठा रहेगी?

माया: *कांग्रेस ने तो आगामी चुनावों को मद्देनजर रख, बड़े लोक-लुभावने नारे दिये हैं, योजनाएं पेश की हैं, विपक्ष के पास इनकी काट के लिए क्या जवाबी औजार हैं?*

वाजपेयी: चुनाव का अंतिम वर्ष नये वायदे करने का नहीं होता, बल्कि पुराने वायदों पर अमल और उपलब्धि के प्रदर्शन का होता है। भारतीय मतदाता भले ही कम पढ़ा-लिखा क्यों न हो, किंतु वह जागरूक है। वह, कौन कितने पानी में है, अच्छी तरह समझता है। ये लुभावने नारे तो डूबते के लिए तिनके का सहारा भी नहीं बन सकते।

माया: *किंतु विपक्ष का क्या जवाबी कार्यक्रम है?*

वाजपेयी: विपक्ष अपना ठोस कार्यक्रम लेकर आयेगा। उदाहरण के लिए रोजगार की स्थायी संवैधानिक गारंटी, जिसमें गांवों के साथ शिक्षित बेरोजगार भी शामिल होंगे। यह मतदाताओं को अधिक आकृष्ट करेगी, बजाय चुनाव राहत योजना के।

माया: *विपक्ष कांग्रेस के अपार धन-संसाधनों के सामने कैसे टिक पायेगा?*

वाजपेयी: यदि विपक्ष में तालमेल हो गया और कांग्रेस को हराने की हवा बन गयी, तो धन, टेलीविजन का दुरुपयोग, लुभावने नारे ये सब कोई काम नहीं आयेंगे।

माया: *कांग्रेस ने तो अपना चुनावी अभियान अभी से चला दिया है, जबकि विपक्ष सरफुटौवल में जुटा लगता है?*

वाजपेयी: सरफुटौवल तो कांग्रेस में भी है और प्रतिपक्ष से कहीं ज्यादा। प्रतिपक्ष मे थोड़ा बहुत मतभेद हो, तो समझ में आता है। किंतु कांग्रेसी आपस में जिस तरह लड़ रहे हैं, वह भी मतदाताओं को दिखायी दे रहा है। सत्ता-परिर्वन निश्चित है

—रंजना कक्कड़,

भूमिका निभाता है। यद्यपि वामपंथियों का मत है कि भाजपा से तालमेल से अल्पसंख्यक मतदाता विपक्ष से भागेगा, किंतु शरद यादव ऐसी संभावना नहीं देखते। उनके अनुसार, "मुस्लिम वोट जीतते दिखाई देते घोड़े के पक्ष में अंततः एकजुट हो जाता है। विपक्ष की जीत का अहसास होते ही, वे उसके पीछे हो जायेंगे, जैसा कि पिछले चुनावों में हुआ है।" यादव की दलील है कि भाजपा से तालमेल पहली बार नहीं हुआ है। १९६७ में तो दक्षिणपंथ-वामपंथ, दोनों साथ थे और मुस्लिम मत विपक्ष पक्ष में पड़ा था। १९७१-७२ में महागठबंधन हुआ था, जिसमें जनसंघ, सोशलिस्ट और कांग्रेस-ओ एक झंडे तले आये थे। १९७७ में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था और मार्क्सवादी पार्टी से तालमेल था। उस समय भी मुस्लिम मतदाताओं ने हमारे पक्ष में मतदान किया था। इसके विपरीत १९८० में जब जनता पार्टी टूटी और जनसंघ भाजपा का रूप धारण कर अलग हुआ, तो मुस्लिम मतदाता हमारे साथ नहीं रुके थे। मूल बात यह है कि संघर्ष तिकोना-चौकोना होने पर वोट बंटे-बिखरेंगे। टक्कर सीधी हुई, तो मुस्लिम मतदाताओं के वोट भाजपा से तालमेल के बावजूद हमारे पक्ष में गिरेंगे।"

लेकिन जनता दल यह कभी नहीं चाहेगा कि वामपंथियो से उसका तालमेल न हो। कांग्रेस का जहां जनता दल और उसके सहयोगी दलों पर यह आरोप है कि वे टिकाऊ सरकार नहीं दे सकते, वहां यह भी है कि वे गरीबों के हमदर्द नहीं। गरीबों के प्रति हमदर्दी का दावा मजबूत करने के लिए ही कांग्रेस 'पंचायत राज' और 'नेहरू रोजगार योजना' का जोर-शोर से ढोल पीट रही है। इसलिए न केवल कार्यक्रमों के जरिये, बल्कि वापपंथियों से भी तालमेल बिठाकर जनता दल यह सिद्ध करना चाहता है कि वह वंचितों का हमदर्द है और इसीलिए वामपंथी उनके साथ हैं।

> महासचिव नंबूदिरीपाद जहां भाजपा से दूरदराज का भी संबंध नहीं चाहते, वहीं ज्योति बसु तालमेल के पक्षधर हैं। वामपंथियों पर तो भाजपाई सीधे-सीधे रूसी दबाव का प्रभाव बताते हैं। भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा के अनुसार, "कम्युनिस्ट हम पर बारंबार सांप्रदायिकता का आरोप इसी मकसद से लगा रहे हैं कि तालमेल संभव ही न हो और कांग्रेस का इस प्रकार अप्रत्यक्ष लाभ हो जाये।"

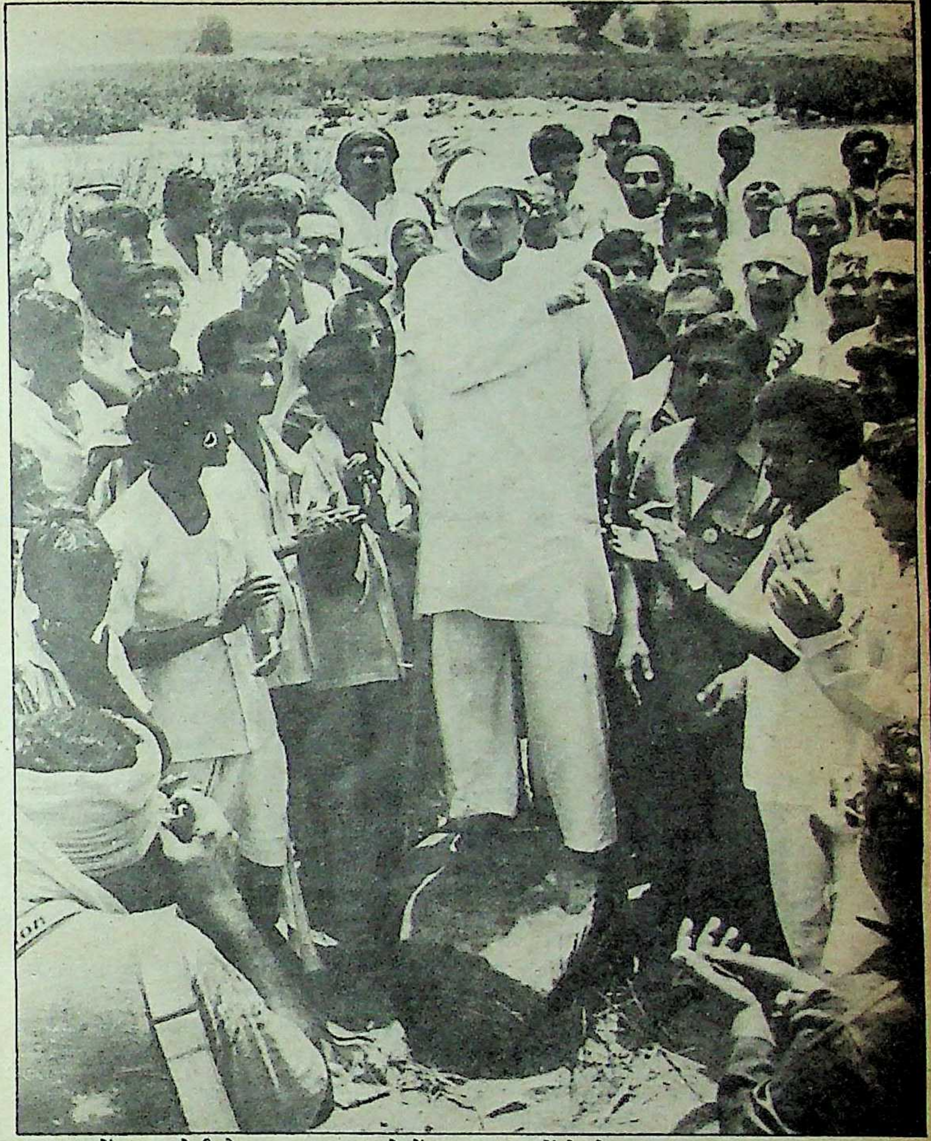
महाराष्ट्र में शरद जोशी के साथ : महाराष्ट्र से तेंदू पत्ता आंध्र में बेचने का आह्वान

जैसा कि तय था, भाजपा से तालमेल करने की जनता दल की इच्छा से पिछले कुछ दिनों से कम्युनिस्ट बिदके-बिफरे हुए हैं। माकपा में स्थिति इसलिए और विषम हुई हैं, क्योंकि तालमेल और भाजपा के प्रश्न पर पार्टी (माकपा) स्वयं दो खेमों में विभाजित बतायी जाती है। महासचिव नंबूदिरीपाद जहां भाजपा से दूरदराज का भी संबंध नहीं चाहते, वहीं ज्योति बसु तालमेल के पक्षधर हैं। वामपंथियों पर तो भाजपाई सीधे-सीधे रूसी दबाव का प्रभाव बताते हैं। भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा के अनुसार, "कम्युनिस्ट हम पर बारंबार सांप्रदायिकता का आरोप इसी मकसद से लगा रहे हैं कि तालमेल संभव ही न हो और कांग्रेस का इस प्रकार अप्रत्यक्ष लाभ हो जाये।"

जवाब में कामरेड फारूकी बोले, "हम हर हाल में जनता दल से तालमेल करने को लालायित नहीं है। जनता दल के लिए सवाल तख्त का अवश्य है, किंतु उसके लिए हम तख्ता (अस्तित्व समाप्त करना) नहीं स्वीकार कर सकते। उप्र, बिहार में हमारी जो जानी-मानी सीटें हैं, उन्हें हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं।" जानकार सूत्रों के अनुसार देवीलाल और भाकपा सचिव कामरेड फारूकी के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें भाकपा ने उप्र और बिहार दोनों जगह भाजपा की तरह दावेदारी पेश कर जनता दल के लिए सांसत खड़ी की है।

जनता दल के लिए वामपंथी कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं, ऐसा लालकृष्ण आडवाणी नहीं मानते। कारण, "लोकसभा की ४२५ सीटों पर वामपंथी क्या करते हैं, क्या नहीं—इसका कोई प्रभाव नहीं पड़नेवाला। भौगोलिक रूप से उनका प्रभाव देश के दो कोनों में सिमट गया है। किंतु दो राज्य सरकारें चलाने के कारण वे जनता दल तथा अन्य विपक्षी पार्टियों पर अनुचित दबाव डालने में सफल रहे हैं।" मार्क्सवादी तालमेल में बाधक होंगे,

इसकी संभावना इसलिए भी क़म है, क्योंकि उनके प्रभाव-क्षेत्रों में जनता दल की कोई खास़ जड नहीं है। तालमेल के फलस्वरूप उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुल सीटों का लाभ अवश्य हो सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि उड़ीसा में बीजू पटनायक से वामपंथियों का पहले ही समझौता हो गया है। विपक्षी नेताओं के अनुसार नंबूदिरीपाद कुछ भी कहें, किंतु अंततः तालमेल होकर रहेगा। सुरेंद्र मोहन तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि वामपंथ का न सिर्फ जनता दल और भाजपा से, बल्कि राष्ट्रीय मोर्चे से भी तालमेल हो जायेगा।

राजनीतिक विवशताएं : विपक्षी तालमेल के पीछे अनेक पर्यवेक्षक कुछ राजनीतिक विवशताएं भी देखते हैं। स्थिति इस समय ऐसी है कि सभी पार्टियों को पक्ष (कांग्रेस) अथवा विपक्ष में से एक को चुनना होगा। वर्तमान कांग्रेस विरोधी जनमत और विपक्षी एकजुटता के माहौल के चलते कांग्रेसी खेमे की ओर कदम बढ़ाना, तो आत्मघाती होगा ही, एकजुट विपक्ष के उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए खडे उम्मीदवारों को भी जनता द्वारा माफ न किये जाने की संभावना है।

> वर्तमान कांग्रेस विरोधी जनमत और विपक्षी एकजुटता के माहौल के चलते कांग्रेसी खेमे की ओर कदम बढ़ाना, तो आत्मघाती होगा ही, एकजुट विपक्ष के उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए खड़े उम्मीदवारों को भी जनता द्वारा माफ न किये जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार चलानेवाली क्षेत्रीय पार्टियों और मोर्चा सरकार चलानेवाली वामपंथी पार्टियों को कर्नाटक में बोम्मई सरकार गिराये जाने से जबरदस्त झटका लगा है। इस वारदात ने उन्हें यह सबक सिखाया है कि संविधान की धारा-३५६ का दुरुपयोग कर कांग्रेस विपक्षी सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। सबको विश्वास हो गया है कि दुबारा सत्तारूढ़ होने पर राजीव गांधी गैरकांग्रेसी सरकारों का सफाया कर देंगे। आत्मरक्षा की यही भावना विपक्षी एकजुटता का मूलाधार बन गयी है। यह एकजुटता चाहे असुरक्षा से ही उत्पन्न हुई हो, लेकिन विपक्ष की एकता की यह भावना विपक्ष का पलड़ा भारी कर देती है।

लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी अपना हौसला बुलंद रखने के लिए यह मानते हैं कि यह एकता

साक्षात्कार : विट्ठल नरहरि गाडगिल,

—कांग्रेस महासचिव,

'कांग्रेस को कोई चिंता नहीं'

माया : *विपक्ष में आज चाहे जितना भी झगड़ा-झंझट हो, किंतु क्या सत्ता की आकांक्षा उन्हें चुनावपूर्व एकजुट नहीं कर देगी ?*

गाडगिल : इसकी कोई संभावना नहीं। जैसा कि बालगंगाधर तिलक का कथन है—शादी के लिए लड़की का १६ वर्ष का होना जरूरी है, लेकिन चार-चार वर्ष की चार लड़कियों को जोड़कर उन्हें विवाह योग्य नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह २० अलग-अलग पार्टियों को एकजुट नहीं किया जा सकता। विपक्ष तो स्वयं बचाव की मुद्रा अपनाने को बाध्य है। जहां प्रधानमंत्री के ५-५ दावेदार होंगे, वहां निरंतर झगड़ा-टंटा बढ़ता रहेगा।

माया : *क्या कांग्रेस धन-भुजबल के सहारे चुनावी सफलता पाने का मंसूबा पाल रही है ?*

गाडगिल : हमें अपनी पांच वर्षों की उपलब्धियों और विपक्ष की कारगुजारियों के आधार पर सहजता से स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा।

माया : *किंतु विपक्ष का दावा है कि वह कांग्रेस को हर हाल हरायेगा ?*

गाडगिल : हराना तो दूर, बराबर की टक्कर का भी सवाल नहीं है। १९७७ की बात और थी। न तो अब वह माहौल है और न जनमत। इलाहाबाद उपचुनाव के बाद विपक्ष ने नित्यप्रति यही अफवाह फैलाई कि कांग्रेस टूट रही है और उसके अधिकांश नेता यहां आ रहे हैं। किंतु हुआ उलटा है। कांग्रेस से छोड़कर जाने के बजाय स्वयं विपक्ष के अनेक नेता कांग्रेस में आये हैं; मसलन, राम नरेश यादव, कमला बहुगुणा, वीपी मौर्य आदि। उनमें (विपक्ष में) जारी सरफुटौव्वल के चलते औरों के आने की भी संभावना है।

माया : *जहां तक सरफुटौव्वल का प्रश्न है, तो कांग्रेस की स्थिति आप बेहतर कैसे कहेंगे ?*

गाडगिल : कांग्रेस में जो थोड़ा बहुत असंतोष व उठापटक थी, उसका समाधान हो चुका है। ताजा मिसाल मध्य प्रदेश की है, जहां कांग्रेस के परस्पर विरोधी गुट आज एकजुट होकर पार्टी की विजय के लिए सक्रिय हो गये हैं। इसी के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है।

माया : *क्या कांग्रेस का सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय विपक्ष की सीधी चुनौती है ?*

गाडगिल : कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। इस समय चुनावी तालमेल की जो बात चल रही है, उसकी सफलता की संभावना बहुत कम दिखायी देती है। विशेषकर इसलिए कि विपक्ष में अंतर्कलह भी है और परस्पर राग-द्वेष भी। इसके चलते यह कहना कि वे ५४२ में से ५४२ सीटों पर सीधी टक्कर देंगे, मात्र एक दिवास्वप्न है। यदि यह असंभव संभव भी हो जाये, तो भी चुनावी गणित ऐसा नहीं है कि विजयश्री इन्हें (विपक्ष को) ही प्राप्त हो। अब तक का अनुभव यही रहा है कि यदि किसी भाजपा उम्मीदवार को टिकट मिलता है, तो यह जरूरी नहीं कि जनता दल के मतदाता उसी को वोट देंगे। एकजुटता का यह गणित कि अगर कांग्रेस को ४०-४५ प्रतिशत मत मिलते हैं, तो शेष ५५-६० प्रतिशत मत सब एकजुट विपक्ष को जायेंगे सही नहीं।

माया : *कांग्रेस की चिंता दो तरह से उजागर है : एक, लुभावने कार्यक्रमों की रिश्वत, दूसरे, वीपी सिंह पर निरंतर हमले।*

गाडगिल : यदि वीपी सिंह का कोई प्रभाव है भी, तो वह उत्तर प्रदेश तक सीमित है और वहां उनकी काट के लिए चंद्रशेखर कमर कसे बैठे हैं। विंध्याचल के नीचे (दक्षिण में) न तो उनका नाम है, न प्रभाव। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने की प्रक्रिया १९८७ से शुरू हो गयी थी। सैकड़ों मुद्दों में से हमने अंततः चार मुद्दे छांटे—एक, चुनाव सुधार, दूसरा, पंचायती राज, तीसरा, पार्टी का पुनर्गठन, चौथा, आर्थिक कार्यक्रम। इसके विपरीत विपक्ष अपने ही झगड़े-झंझट में लगा है।

—रंजना कक्कड़,

हमारी अपनी तैयारी है: अटल की जनसभा

फलदायी नहीं होगी। राजनीतिक पर्यवेक्षक डीपी त्रिपाठी विपक्षी सफलता की संभावना से साफ-साफ इनकार करते हुए कहते हैं, "विपक्ष की सैद्धांतिक और व्यावहारिक नींव ही गड़बड़ है। कांग्रेस के विरुद्ध विकल्प दो ही सूरत में बनता है। एक, समूचे देश में राजनीतिक आधारवाला कोई दल हो, जबकि विपक्ष का कोई भी दल, यहां तक कि जनता दल भी इस पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि अनेक राज्यों में उसका अस्तित्व नगण्य है। दूसरे, विपक्ष वास्तविक अर्थों में एक संघीय विकल्प बनाये। फिलहाल यह भी संभव नहीं लगता। विपक्ष को जनसाधारण इसलिए स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह देश की एकता, अखंडता और स्थायित्व की गारंटी नहीं देता।"

कांग्रेस महासचिव वीएन गाडगिल तो सीधे-सीधे पहले विपक्षी एकजुटता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं, फिर उसके चुनावी गणित पर। उनके अनुसार, "५४२ सीटों पर तालमेल की आशा करना दिवास्वप्न देखना है। यदि तालमेल हो भी गया, तो इस बात की संभावना नहीं कि जो भी विपक्षी उम्मीदवार खड़ा होगा, उसे ही अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता समर्थन और वोट देंगे और दिलायेंगे।" (देखिए साक्षात्कार) गाडगिल का अनुमान है कि ५४२ सीटों पर सीधी टक्कर संभव नहीं, लेकिन ४०-५० सीटों पर तिकोनी-चौकोनी मुठभेड़ हो सकती है।

यह माना जा सकता है कि विपक्षी मतों को अविभाजित रखने के लिए विपक्ष कमोबेश कारगर समरनीति पर चल रहा है। लेकिन मात्र दलों की एकजुटता ही जीत की गारंटी नहीं है। यद्यपि चुनाव घोषणा-पत्र पढ़कर मतदाता मतदान नहीं करते, लेकिन चुनाव के ऐन पहले आकर्षक कार्यक्रम और लोकलुभावनकारी नारे मतदाता को रिझाने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं।

यह माना जा सकता है कि विपक्षी मतों को अविभाजित रखने के लिए विपक्ष कमोबेश कारगर समरनीति पर चल रहा है। लेकिन मात्र दलों की एकजुटता ही जीत की गारंटी नहीं है। यद्यपि चुनाव घोषणा-पत्र पढ़कर मतदाता मतदान नहीं करते, लेकिन चुनाव के ऐन पहले आकर्षक कार्यक्रम और लोकलुभावनकारी नारे मतदाता को रिझाने में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। श्रीमती गांधी 'गरीबी हटाओ' और राजीव गांधी १९८४ में 'देश की अखंडता खतरे में है' के नारे लगाकर चुनाव जीत चुके हैं। इस चुनाव के पूर्व राजीव गांधी ने 'जनता को सत्ता' और हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लुभावने कार्यक्रमों पर अमल करना शुरू करा दिया है। टीवी पर रोजाना अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नौकरी देने की खास मुहिम का जमकर विज्ञापन हो रहा है। इस चुनाव-प्रसाद और प्रलोभन का विपक्ष के पास क्या जवाब है? तेलुगूदेशम के सांसद व राष्ट्रीय मोर्चा के महासचिव पी उपेंद्र कांग्रेस की इस मुहिम से चिंतित नहीं लगते। शासक दल द्वारा धन-साधन के जरिये चुनावी पहलकदमी करना उन्हें कोई नयी बात नहीं लगती। वे कहते हैं, "उनके पास धन-साधन हैं, तो

साक्षात्कार : **सी राजेश्वर राव,**

—भाकपा महासचिव

'हम कांग्रेस और भाजपा, दोनों से लड़ेंगे'

माया : *वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष की दशा और दिशा क्या है ?*

राव : विपक्ष में अनेक पक्ष हैं। वामपंथी पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं और सरमायेदारी का रास्ता अपनानेवाली पार्टियां हैं। मौजूदा हालात में सांप्रदायिक रास्ता अपनानेवाली पार्टियों से देश की एकता, अखण्डता को बेहद खतरा है। इसलिए हम ऐसी पार्टियों का पूर्ण विरोध करते हैं। सरमायेदारपरस्त जो राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ धर्मनिरपेक्षतावाद, प्रगतिशील विदेश नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भूस्वामियों के शोषण के खिलाफ मुहिम आदि के समान कार्यक्रमों के आधार पर हमारा संबंध हो सकता है। हमारी पार्टी मात्र चुनावी पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह विफल रही है। इसीलिए हम कांग्रेस को अपदस्थ करना चाहते हैं, जिससे कि वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील ताकतों का विकल्प उभरे। किंतु यह विकल्प महज बातचीत से आनेवाला नहीं। अवाम की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षों-आंदोलनों से ही यह आयेगा।

माया : *भाकपा का असली शत्रु कौन है, कांग्रेस या भाजपा ?*

राव : हम कांग्रेस और भाजपा दोनों से लड़ेंगे। इनके साथ हमारा कोई मोर्चा नहीं बन सकता। जहां तक सीटों के तालमेल की बात है, उस पर हम चुनाव नजदीक आने पर ही विचार करेंगे।

माया : *किंतु आपकी पार्टी और जनता दल में तालमेल की बातचीत तो प्रारंभ हो गयी है ?*

राव : प्रारंभिक बातचीत हुई है। हमने उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्रों और सीटों की जानकारी दी है।

माया : *सीधी टक्कर में कांग्रेस की हार जो अपरिहार्य मानी जाती है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?*

राव : सीधी टक्कर को अमल में लाना कठिन है। पहले तो अपनी ही पार्टी में वे (गैर कम्युनिस्ट विपक्ष) इसे सुनिश्चित करें। जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां हम अवश्य ही लड़ेंगे।

माया : *भाजपा का आरोप है कि ४५० लोकसभा सीटों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव नगण्य है, खासकर हिंदीभाषी क्षेत्रों में।*

राव : यह कहना बिलकुल गलत है कि हमारे प्रभावक्षेत्र सीमित हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या भाजपा को ठेका दिया गया है ? खुद भाजपा अकेले लड़कर कितनी सीटें हासिल कर सकती है ?

माया : *यदि विपक्ष जीता, तो खिचड़ी सरकार ही बन सकेगी। क्या वह वर्तमान सरकार से बेहतर होगी ?*

राव : यदि कार्यक्रम आधारित विपक्षी सरकार बनेगी, तो वह कारगर होगी। पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार यद्यपि संयुक्त मोर्चा सरकारें हैं, किंतु उन्हें आप खिचड़ी सरकार नहीं कह सकते। वे स्थायी हैं, क्योंकि कार्यक्रम पर आधारित हैं। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस की वे राज्य सरकारें हैं, जिन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त है, फिर भी वहां स्थिरता नहीं। मुख्यमंत्रियों को लगातार बदलना पड़ा है।

माया : *आगामी चुनाव में विपक्ष का भविष्य आपको कैसा लग रहा है ?*

राव : आगामी चुनाव में अगर कार्यक्रम के आधार पर सभी वामपंथी, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इकट्ठी हो जायेंगी, तो विपक्ष की जीत सुनिश्चित है।

माया : *बावजूद इसके कि कांग्रेस धन-संसाधन की दृष्टि से विपक्ष से कहीं आगे है ?*

राव : धन-संसाधन से कुछ होनेवाला नहीं। हिन्दुस्तान का अवाम काफी सजग है। यदि उसे सही बात बतायेंगे, मार्ग दिखायेंगे, तो वह कांग्रेस को अवश्य अपदस्थ करेगा।

—रंजना कक्कड

हमारे साथ जनता है। जनता कांग्रेसी हथकंडों को भलीभांति जानती-पहचानती है, क्योंकि राजीव गांधी ऐन चुनाव-पूर्व अनापशनाप घोषणाएं करने के लिए विख्यात हैं। प० बंगाल में विधानसभा-चुनाव के पूर्व १००० करोड़ रुपए, हरियाणा में ४५० करोड़ और इसी प्रकार तमिलनाडु में करोड़ों की योजनाओं की घोषणा की गयी थी। यहां तक कि ५ करोड़ रुपए तो राजीव का गुणगान करते वीडियो वैन पर खर्च किये गये, किंतु नतीजा सिफर निकला। यही इतिहास पुनः दोहराया जायेगा।"

हर कार्यक्रम की काट : लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष मात्र यही आस लगाये बैठा है कि हाल में कांग्रेस द्वारा घोषित योजनाओं का मतदाता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में तैयार हो रहे घोषणा-पत्र में कांग्रेस के हर कार्यक्रम की काट का प्रबंध किया गया है। मसलन, कांग्रेस की बहुप्रचारित जवाहर रोजगार योजना के जवाब में 'काम के अधिकार' को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। इस पर करीब एक करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने की मुहिम शुरू हो गयी है। १५ अगस्त, १९८९ को समूचे देश में 'पूर्ण रोजगार' दिवस के रूप में मनाने

> विपक्ष का तर्क है कि वर्तमान सरकार विदेशी माहौल में पले विदेशी सोच में ढले और विदेशी कंपनियों के पक्षधर लोग चला रहे हैं; जबकि विपक्ष देश को आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव से संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दोनों ओर से प्रलोभन : कांशीराम

अलीगढ़ का गोलीकांड कांग्रेस के लिए महंगा पड़ेगा: टिकैत की पंचायत

की योजना है, जिसमें एक ओर, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया जायेगा, दूसरी ओर, रोजगार कार्यालयों पर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन और धरने आदि आयोजित किये जायेंगे। कांग्रेस के 'पंचायत राज' के जवाब में उसने 'पंचायत माडल' देने की घोषणा की है।

आरक्षण की पुन: घोषणा कर कांग्रेस ने अनुसूचित जाति-जनजाति को लुभाने-रिझाने का जो प्रयास किया है, उसकी पोल खोलने के लिए जनता दल ने ऐलान किया था कि यदि प्रधानमंत्री तीन महीने के अंदर अपना वादा पूरा नहीं कर पाये, तो १६ अगस्त से एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया जायेगा।

आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्र की ऋणग्रस्तता के खिलाफ संघर्ष और अभियान को विशेष स्थान दिया गया है। जनता दल २ अक्तूबर को 'कर्जमुक्ति दिवस' के रूप में मनायेगा। १० हजार तक के कर्जदारों को कर्ज न चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही ऐलान किया गया है कि सत्तारूढ़ होने पर सभी कर्ज माफ कर दिये जायेंगे।

अखबारी कागज को धुआंधार महंगा करने और 'स्टेट्समैन' तथा इंडियन पोस्ट' को डराने-धमकाने की अद्यतन घटनाओं को प्रेस और बुद्धिजीवी वर्ग ने बहुत गंभीरला से लिया है। इसे प्रेस पर अघोषित सेंसर की संज्ञा दी जा रही है। दूसरी ओर टीवी-रेडियो का चुनाव पूर्व विपक्ष के खिलाफ जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बुद्धिजीवीवर्ग के लिए नागवार गुजर रहा है। प्रेस और सरकारी माध्यमों के प्रति सरकारी रवैये को देखकर विपक्ष ने बेहतर वैकल्पिक नीति की घोषणा की है। रेडियो, टीवी डीएवीपी और फिल्म्स डिवीजन को एक स्वायत्तशासी निगम के अधीन करने का विपक्ष ने संकल्प व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त 'सरकारी गोपनीयता' के कालीन के नीचे दबायी जाने वाली सूचनाओं को उघाड़ने के लिए 'सूचना की स्वतंत्रता' का कानून बनाने की भी घोषणा की गयी है।

विपक्ष को सबसे बड़ी उम्मीद अपने 'स्वदेशी बनाम विदेशी' नारे से है। जिस प्रकार क्षेत्रीय गौरव को भुनाकर क्षेत्रीय दलों ने सत्ता पायी है, उसी का विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करने की सोच रहा है। विपक्ष का तर्क है कि वर्तमान सरकार विदेशी माहौल में पले, विदेशी सोच में ढले और विदेशी कंपनियों के पक्षधर लोग चला रहे हैं, जबकि विपक्ष देश को आत्मनिर्भर ओर आत्मगौरव से संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरेंद्र मोहन के अनुसार, "विपक्ष का नारा यही होगा कि निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार से लिप्त उस सरकार को हटाओ जो देश को विदेशी पूंजीवाद के अधीन बना रही है। हमारा वायदा होगा आत्मनिर्भर देश, पूर्ण रोजगार और किसानों की कर्जमुक्ति।" वीपी सिंह का मानना है कि जो सरकार मात्र सरकारी मीडिया के जरिये जनता को सब्जबाग दिखा रही है, उसे यह मालूम होना चाहिए कि अब बात दूर तलक निकल कर जनता के बीच पहुंच गयी है।

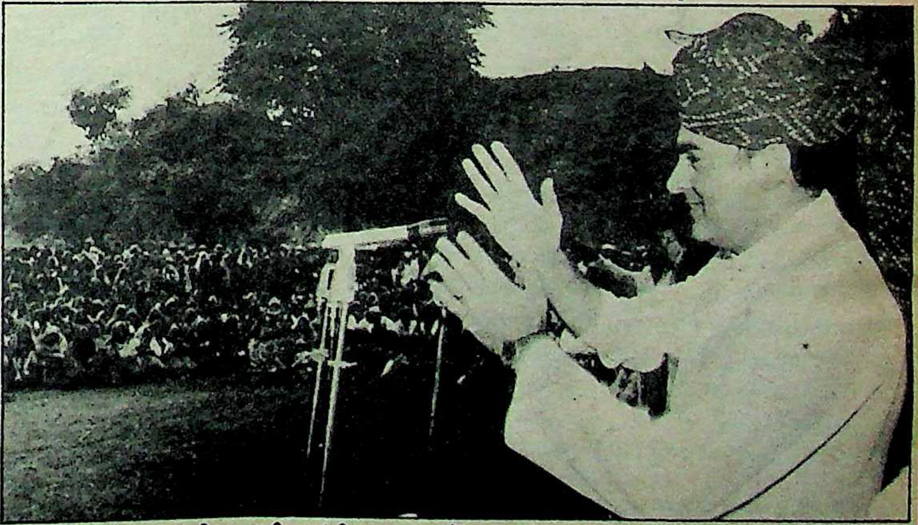

देहात के प्रति नवजात स्नेह: राजीव गांधी राजस्थान में

चुनावी गणित और रणनीति

अगर सभी विपक्षी दल इंका के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और इंका को १९८० जितने वोट ही मिलते हैं, तो शासक दल उत्तर प्रदेश में अधिक-से-अधिक २४ और बिहार में १५ स्थान ही जीत पायेगा। सभी जानते हैं कि अगर शासक दल के पांच फीसदी वोट भी खिसका लिये जायें, तो सत्ता में बैठी पार्टी के लिए कुरसी बचाये रखना मुश्किल हो जायेगा। १९५२ के बाद पहली बार १९६७ में ऐसा हुआ था और कांग्रेस को केंद्र में एक अल्पमत सरकार चलानी पड़ी थी और नौ राज्य तो उसके हाथ से निकल ही गये थे। अगर आज की स्थिति में राज्यों पर अलग-अलग विचार किया जाये, तो मात्र तीन फीसदी वोट कट जाने से कांग्रेस की फिर वही हालत हो जायेगी।

विजय का गणित: लेकिन विपक्ष का गणित या उसकी उम्मीदें एक और हिसाब पर टिकी हैं। यह हिसाब है गैरकांग्रेसी मतों के विभाजन का। दो उम्मीदवार होने पर १०० वोट में से जिसे भी ५१ या उससे अधिक वोट मिलेंगे, वह जीतेगा, लेकिन अगर यही वोट तीन उम्मीदवारों में बंट जायें तो ३४ वोट पानेवाला भी जीत सकता है। इनके बीच ३४, ३३ और ३३ मत जैसा विभाजन भी हो सकता है। उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दीजिए, तो कोई आदमी १०० में से २५ वोट पाकर भी जीत सकता है। जैसे १९८० में जनता पार्टी का उम्मीदवार जमशेदपुर से २९ फीसदी वोट पाकर ही जीत गया था और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इंका उम्मीदवार ३२ फीसदी वोट पाकर जीता था।

इस बार राजीव-समर्थक लहर होने की जगह इंका शासन के प्रति निश्चित रूप से लोगों के मन में गुस्सा है और इस सरकार के नेता राजीव गांधी के प्रति भी उनके मन में नाराजगी है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजीव गांधी दिन-रात टीवी पर दर्शन देने, जवाहर रोजगार योजना चलाने और पंचायती राज के जरिये लोगों को सत्ता सौंपकर अधिक-से-अधिक उतनी ही सीटें हासिल कर सकते हैं, जितनी उनकी मां ने १९८० में हासिल की थीं।

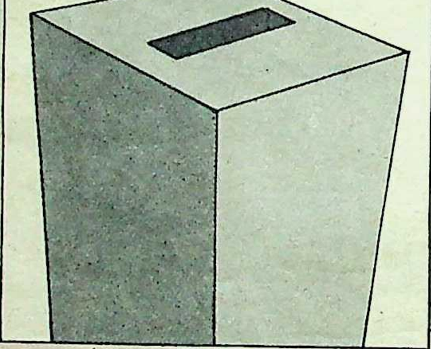

इसलिए विपक्षी दल भी जानते हैं कि जब शासक दल के खिलाफ या पक्ष में कोई हवा न बह रही हो, तो शासक दल को हराने का सबसे बढ़िया तरीका उसके खिलाफ एकजुट हो जाना ही है। इस प्रकार अगर शासक दल के उम्मीदवार को नहीं मिलनेवाले मत विभाजित नहीं होते, तो विपक्षी उम्मीदवार ४५ से ४८ फीसदी वोट पाकर भी जीत सकते हैं। १९८५ मे राजीव गांधी के लिए एक सहानुभूति लहर थी, जबकि १९७७ में आपातकाल की ज्यादतियों के कारण इंदिरा गांधी के खिलाफ हवा बह रही थी। १९८० में कोई लहर नहीं थी, लेकिन वर्ष से अधिक समय तक शासन करनेवाली जनता पार्टी से लोग निराश जरूर थे।

विपक्ष की उम्मीदें: आज विपक्ष दो महत्वपूर्ण कारणों से अपनी जीत के बारे में अधिक आश्वस्त है। इस बार राजीव-समर्थक लहर होने की जगह इंका शासन के प्रति निश्चित रूप से लोगों के मन में गुस्सा है और इस सरकार के नेता राजीव गांधी के प्रति भी उनके मन में नाराजगी है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजीव गांधी दिन-रात टीवी पर दर्शन देने, जवाहर रोजगार योजना चलाने और पंचायती राज के जरिए लोगों को सत्ता सौंपकर अधिक-से-अधिक उतनी ही सीटें हासिल कर सकते हैं, जितनी उनकी मां ने १९८० में हासिल की थीं। लेकिन इतनी सीटें भी पाना

१९८० चुनाव: इंका को हिंदी-भाषी राज्यों में मिले मत

प्राप्त मतों का प्रतिशत	उत्तर प्रदेश		बिहार		मध्य प्रदेश		राजस्थान		हरियाणा	
	चुनाव क्षेत्र	जीती सीटें	चुनाव क्षेत्र	जीती सीटें	चुनाव क्षेत्र	जीती सीटें	चुनाव क्षेत्र	जीती सीटें	चुनाव क्षेत्र	जीती सीटें
० से ३६	४५	१३	२२	१	२	२	६	२	७	२
३७ से ३९	८	७	८	५	१	—	२	२	१	१
४० से ४२	८	७	९	९	३	२	१	१	१	१
४३ से ४५	९	९	३	३	७	५	५	३	—	—
४६ से ४८	८	८	१	१	७	६	३	२	—	—
४९ से ५०	२	२	६	६	५	५	२	२	—	—
५० से अधिक	५	५	५	५	१५	१५	६	६	१	१
कुल योग:	८५	५१	५४	३०	४०	३५	२५	१८	१०	५

उक्त तालिका से क्रमशः यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने कितने चुनाव क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मत मिलने पर कितने स्थान जीते।

बहुत मुश्किल है और इसका कारण है १९८० और १९९० की स्थिति में अंतर। अब कुल ४१ करोड़ मतदाताओं में मुस्लिम मतदाता साढ़े छह करोड़ हैं जिनमें से अधिकांश मुसलमान राजीव गांधी से नाराज बैठे हैं।

ऐसे में विपक्ष की रणनीति बहुत ही सीधी है। उनके लिए सबसे पहला काम तो यही प्रबंध करना है कि गैर-कांग्रेसी वोट बंटें नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें यह पक्की व्यवस्था करनी होगी कि अधिक-से-अधिक स्थानों पर इंका से सीधा मुकाबला हो। पांच हिंदी-भाषी राज्यों तथा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में ऐसा होना और भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश, केरल और प० बंगाल में अधिकांश स्थानों पर सीधा मुकाबला होगा ही और इसके लिए विपक्षी दलों के बीच तालमेल की नयी कोशिशों की कोई दरकार नहीं होगी।

विपक्षी एकता का मुद्दा: हिंदी-भाषी राज्यों के लिए विपक्षी एकता या कम-से-कम सीटों का तालमेल सबसे जरूरी चीज है। इन पांच राज्यों—उप्र, मप्र, बिहार, राजस्थान और हरियाणा—में लोकसभा की २१४ सीटें हैं। अगर इसमें दिल्ली की भी सात सीटें जोड़ ली जायें, तो यह संख्या २२१ हो जायेगी। १९८० में कांग्रेस ने इन पांच राज्यों में १४५ सीटें हासिल की थीं जबकि उसे कुल प्राप्त लोकसभा सीटों की संख्या ३५३ थी। १९९० में हालात कुछ अलग हैं। तमिलनाडु में अगर इंका द्रमुक या अन्नाद्रमुक के जयललिता गुट के साथ समझौता करती है तो भी उसे वहां आधी सीटें भी नहीं मिल पायेंगी। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव आज भी इंका पर भारी पड़ते हैं और इंका वहां की ४२ में से १० से अधिक सीटें जीत पाने की उम्मीद नहीं कर सकती। १९८० की तुलना में आज इंका गुजरात में और बुरी स्थिति में है और कर्नाटक में हाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वहां इंका की स्थिति क्या रहेगी?

> **जनता दल या अन्य विपक्षी दलों के लिए मुख्य लक्ष्य इंका को परास्त करना है, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाना नहीं, क्योंकि इंका के पराजित होने के बाद सभी या अधिकांश विपक्षी दलों के लिए गठबंधन बनाकर मिलीजुली सरकार बनाने का रास्ता आसान हो जायेगा। अभी कोई भी एक विपक्षी पार्टी अपने दम पर बहुमत पाने की स्थिति में नहीं है।**

परिणामस्वरूप इंका को संसद में २६५ या २७२ स्थान (लोकसभा में कुल ५४२ स्थान है और अगर पंजाब में चुनाव नहीं कराये गये तो सिर्फ ५२९ स्थानों पर ही चुनाव होंगे।) पाकर बहुमत हासिल करने के लिए हिंदी-भाषी राज्यों में कम-से-कम १५० स्थान हासिल करने होंगे। जनता दल या अन्य विपक्षी दलों के लिए मुख्य लक्ष्य इंका को परास्त करना है, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाना नहीं। क्योंकि इंका के पराजित होने के बाद सभी या अधिकांश विपक्षी दलों के लिए गठबंधन बनाकर मिलीजुली सरकार बनाने का रास्ता आसान हो जायेगा। अभी कोई भी एक विपक्षी पार्टी अपने दम पर बहुमत पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हर विपक्षी दल यह भलीभांति समझता है कि जो भी दल विपक्षी एकता में बाधक होगा अथवा उसके (विपक्ष के) वोट काटने का जिम्मेदार होगा, वह कांग्रेस को पराजित करनेवाले मतदाताओं का कोपभाजन बनेगा और ऐसे मतदाताओं की तादाद—इस हकीकत के बावजूद कि कांग्रेस को १९८० व १९८४ में बहुमत प्राप्त हुआ था—बहुत बड़ी है। मसलन १९८० में उप्र में कांग्रेस को केवल ३५ प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिया था, किंतु उसे ८५ सीटों में से ६० प्रतिशत सीटें हासिल हुई थीं। इसका कारण कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन था। अखिल भारतीय विपक्ष को आधे से अधिक वोट प्राप्त हुए थे, किंतु सीटें एक तिहाई से थोड़ा ही अधिक प्राप्त हुई थीं।

उप्र, बिहार की कुल मिलाकर १३९ लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस यदि पांच हिंदी-भाषी राज्यों से १५० सीटें जीतना चाहती है, तो उसे इन दोनों राज्यों (उप्र, बिहार) से कम-से-कम ९० सीटें जीतनी होंगी। किंतु विपक्षी एकता कायम होने की स्थिति में कांग्रेस के लिए १३० सीटों में से ५० सीटें जीत पाना भी मुश्किल होगा। मसलन, बिहार में १९८० में कांग्रेस ४२ प्रतिशत या इससे कम वोट प्राप्त कर १५ सीटें जीत सकी थी। सीधी टक्कर में वह इन १५ में से एक भी सीट नहीं जीत सकेगी, भले ही १९८० के मुकाबले इस बार उसके वोटों के प्रतिशत में २ से ३ प्रतिशत वृद्धि ही क्यों न हो जाये। उप्र में कांग्रेस को कुल ५१ सीटें मिली थीं, इनमें से २८ सीटों पर वह ४३ प्रतिशत या इससे कम वोट पाकर जीती तथा ९ सीटों पर उसकी विजय ४३ से ४५ प्रतिशत वोट पाकर हुई (देखें तालिका)। मतदाताओं को पता है कि गैरकांग्रेसी वोटों का विभाजन यदि नहीं हुआ, तो सभी ३७ सीटें विपक्ष की झोली में जायेंगी और कांग्रेस को केवल १४ सीटें प्राप्त होंगी, भले ही १९८० के उसके सौभाग्यशाली दिन क्यों न लौट आयें? **—कुमारेश चक्रवर्ती**

जातीय और धार्मिक मुद्दे: चुनावों में जातीय और धार्मिक गणित अहम भूमिका निभाता है। धर्मगत चुनाव रणनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है बाबरी-रामजन्मभूमि का विवाद। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव-पूर्व इस विवाद के संबंध में कोई दो-टूक फैसला हो सकेगा। विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही कह दिया है कि उसे अदालत का फैसला मान्य नहीं होगा। अतः लगता तो यही है कि गतिरोध फिलहाल ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। लेकिन यदि इस स्थिति में परिवर्तन होता है, तो यह चुनाव की शक्ल बदल सकता है। यद्यपि हरिजनों के वोट हासिल करने के लिए आरक्षण का फिर से पासा फेंका गया है, लेकिन उत्तर भारत में कांशीराम का रुख स्थितियां बदल सकता है। अभी तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही कांशीराम पर गुपचुप दांव फेंक रहे हैं, लेकिन कांशीराम का कोई निर्णायक बयान नहीं आया है। पिछड़ों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पिछड़ों को अमनी पार्टी में शामिल करने और उन्हें महत्व देने लगी है। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के आश्वासन और देवीलाल-अजीत सिंह के कारण पिछड़ों का रुख विपक्ष की ओर ही ज्यादा रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में टिकैत की ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाल में अलीगढ़ में किसानों पर हुई पुलिस की गोलीवर्षा और पहले का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं लगता।

> केंद्र और महत्वपूर्ण हिंदी क्षेत्रों में कांग्रेस के पास सत्ता-बल है, तो विपक्ष के पास भी हरियाणा, तमिलनाडु, असम, आंध्र, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस ने अपनी कितनी ही स्थिति सुधारी हो, विपक्ष भी कम पानी में नहीं है।

यह ठीक है कि पिछले जून के बाद विपक्ष के बढ़ते प्रभाव को पिछले दो तीन महीनों में कांग्रेस ने आक्रामक अभियान चलाकर धूमिल किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने संगठन और कार्यक्रमों की घोषणा के स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। केंद्र और महत्वपूर्ण हिंदी क्षेत्रों में कांग्रेस के पास सत्ता-बल है, तो विपक्ष के पास भी हरियाणा, तमिलनाडु, असम, आंध्र, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस ने अपनी कितनी ही स्थिति सुधारी हो, विपक्ष भी कम पानी में नहीं है।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

राजभाषा समिति के विदेश दौरे

हिंदी के साथ फिर सौतेला सलूक

गृहमंत्री बूटा सिंह ने संसदीय राजभाषा समिति का विदेश दौरा स्थगित कर क्या सचमुच हिंदी का अपमान किया है? जो लोग इस स्थगन से कुपित हैं, वे क्या दूध के धोये हैं?

संसद की राजभाषा समिति के विदेश दौरों की 'निरर्थक फिजूलखर्ची' पर उंगली उठानेवाले कुछेक सदस्यों के आगे आखिर सरकार झुक ही गयी। संभवत: झुकने का सबब यह है कि 'हिंदी के नाम पर लाखों रु० खर्च और काम कुछ नहीं' का प्रचार बहुमत बनानेवाले हिंदी क्षेत्र में तूल न पकड़ ले। पहले से ही कई विवादों से घिरी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव-वर्ष में भाषा के संवेदनशील विवाद से घिरने का जोखिम नहीं उठा सकती, सो गृहमंत्री बूटा सिंह ने इस साल जून के पहले हफ्ते में प्रस्तावित राजभाषा समिति के विदेश दौरे स्थगित कर दिये। लेकिन क्या सरकार इस विवाद में घिरने से बच गयी? हाल यह है कि जहां विपक्ष ने इस मुद्दे को मतदाताओं के सामने लाने के लिए कमर कस ली है, वहीं दौरों का एकतरफा स्थगन अपने आप में एक विवाद बन गया है और विपक्षियों के साथ-साथ सत्तारूढ़ दल के सांसद भी विदेश दौरे टाले जाने के विरोध में मुखर हो गये हैं।

विरोध के मुद्दे : शुरुआत भाजपा सांसद और संसदीय राजभाषा समिति के वरिष्ठ सदस्य अटलबिहारी वाजपेयी के त्यागपत्र से हुई। फिर तो जैसे राजभाषा समिति के प्रस्तावित विदेश दौरों के स्थगन के विरोध का तांता ही लग गया। समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री बूटा सिंह को पत्र भेजकर विरोध प्रकट करनेवालों में कांग्रेसी सांसद रत्नाकर पाण्डेय और नरेशचंद्र चतुर्वेदी अग्रणी रहे। दौरों के ऐन पूर्व उसके स्थगन के निर्णय से क्षुब्ध सदस्यों के रोष के दो प्रमुख कारण बताये जाते हैं। प्रथम यह कि उन्होंने इस स्थगन को राजभाषा हिंदी के प्रति सौतेले व्यवहार की ही एक कड़ी करार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार, "विदेश जानेवाले प्रतिनिधि-मंडलों की कमी नहीं। अधिकांश का काम केवल सद्भावना का प्रचार-प्रसार ही होता है। उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? ऐसा लगता है कि हिंदी के नाम पर विदेश जाना सबसे बड़ा जुर्म है।"

डा० बापू कालदाते

विरोध का दूसरा कारण समिति अध्यक्ष द्वारा बिना समिति की बैठक बुलाये अथवा सदस्यों से विचार-विमर्श किये निर्णय लेना रहा। विरोधियों के अनुसार दौरे का निर्णय समिति की बैठक में समुचित विचार-विमर्श के उपरांत लिया गया था अत: स्थगन का एकतरफा फैसला उचित नहीं। नतीजतन निर्णय के पीछे अधिकांश सदस्यों को दबाव की रणनीति की सफलता ही दिखायी दी। नरेशचंद्र चतुर्वेदी बोले, "समितियों के फैसले आम सहमति से होते हैं। एक के कहने से नहीं। फिर इस समिति को संविधान द्वारा विशिष्ट स्थान दिया है। इसकी जवाबदेही संसद से नहीं, सीधे-सीधे राष्ट्रपति से है। अत: इसके दौरों के स्थगन के अपरिहार्य कारणों की जानकारी जरूर दी जानी चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि तीन गुटों में विभाजित राजभाषा समिति के २६ सदस्यों की जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित विदेशयात्रा तब खटाई में पड़ गयी जब समिति के ही एक सदस्य, जनता दल सांसद डा० बापू कालदाते ने उक्त दौरों को 'अनावश्यक' और 'धन की बर्बादी' करार दे इन शिष्टमंडलों में शामिल होने से इनकार कर दिया और साथ ही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री को विरोधपत्र भी लिख भेजे। आग में घी का काम जाने-माने कम्युनिष्ट सांसद इंद्रजीत गुप्त के इस वक्तव्य ने किया कि बोफोर्स कांड के घपलों की जांच के लिए बनी संसदीय समिति को जब विदेशी मुद्रा की कमी के बहाने स्वीडन जाने से रोक दिया गया, तो हिंदी का विकास देखने के नाम पर विदेशी मुद्रा का संकट कैसे मिट गया?

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति की पिछले वर्ष २६ दिसंबर की बैठक में विदेशयात्रा का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। बैठक में मौजूद अध्यक्ष बूटा सिंह ने भी सिद्धांत रूप में सहमति प्रकट की थी। कदाचित कालदाते उसमें मौजूद नहीं थे। फिर भी चूंकि समितियों के फैसले आम सहमति से होते हैं, सर्वसम्मति से नहीं, इसलिए यह नियम उन पर लागू था। किंतु स्वीकारना तो दूर, उन्होंने फटाफट पत्रकार सम्मेलन बुला लिया और उक्त फैसले की खुली आलोचना कर रंग में भंग तो डाली ही, साथ में आरोपोंवाला भानमती का पिटारा भी खोल दिया। फिर क्या था, ऐसे दौरों को 'हिंदी के प्रसार के नाम पर हवाखोरी और सैरसपाटे का बहाना' नाम मिल गया। आलोचना का प्रमुख मुद्दा यह रहा कि विदेशों में हिंदी के कामकाज के बारे में जानकारी के लिए

बापू कालदाते अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को कठघरे में खड़ा करके यह उजागर करना चाहते थे कि देश में तो राजभाषा (हिंदी) ठीक ढंग से काम कर नहीं रही है और उसे भरपूर समर्थन-सहयोग नहीं मिल पा रहा है, फिर विदेशों में इसकी जांच क्यों करायी जा रही है? बापू कालदाते द्वारा उठायी गयी आपत्ति में राजभाषा के प्रति समर्पण कम है, राजनीतिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति अधिक है।

सांसदों के बड़े-बड़े दलों को विदेश भेजने की क्या आवश्यकता है? यह काम तो प्रश्नावली का उपयोग कर घर बैठे आसानी से और मामूली खर्च से संपन्न हो सकता है।

एक विशेष भेंट में 'माया' द्वारा यह सवाल उठाये जाने पर नरेशचंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, "यदि प्रश्नावली द्वारा वस्तुस्थिति जानी जा सकती हो, तो देश में कभी किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं।" उनका दावा रहा कि दौरों के दौरान प्राप्त की गयी जानकारियां आगामी सितंबर-अक्तूबर में राष्ट्रपति को दी जानेवाली रिपोर्ट में सहायक सिद्ध होतीं।

दौरे के उद्देश्य: १९७५-७६ से काम कर रही इस समिति की सदस्यता संसद में पार्टियों के प्रतिनिधित्व के अनुपात से तय की जाती है। समिति के सदस्य पहले भी विदेशों के दौरे पर जाते रहे हैं, पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देने में लगातार विफल रहे हैं। वर्तमान समिति ने पहली बार, पिछले तीन वर्षों में तीन रिपोर्टें प्रेषित की हैं। चौथी की तैयारी चल रही है जिसमें शिक्षा, जनसंचार, राजनयिक कार्यो संबंधी सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। सदस्यों का मानना है कि विदेशों में राजभाषा हिंदी की स्थिति और उसके प्रचार में आने वाली कठिनाइयों को जाने बिना कोई भी तथ्यात्मक विवरण और टिप्पणियां प्रस्तुत करना कठिन होगा। अतः व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुति के लिए 'स्पाट स्टडी' करना उपयुक्त होता। इसलिए सवाल मात्र सैरसपाटे का नहीं था।

सदस्यों के अनुसार समिति यह भी अध्ययन करना चाहती थी कि जिन देशों में एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, वहां की भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। कई देश भारत की तरह बहुभाषी हैं, हम उनके अनुभवों का भरपूर लाभ उठा सकते थे। किंतु वाजपेयी के अनुसार, "राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हैं, चंद लोगों ने अपने 'हिंदी विरोधी' दृष्टिकोण के कारण अधर में लटका दिया।"

डा० कालदाते का इससे सहमत न होना लाजिमी है। उनके अनुसार १९८० में भी तो राजभाषा समिति का दौरा हुआ था। उसने वहां क्या किया? उसके क्या अनुभव रहे? उसने क्या सिफारिशें की थीं?" स्थिति यह है कि हमारे १४० में से सिर्फ छह दूतावासों में हिंदी अधिकारी हैं। हम विदेशों में जाने के बजाय यहां बैठे-बैठे ही सिफारिश कर सकते हैं कि हमारे अधिकतर दूतावासों में हिंदी अधिकारी होने चाहिए। इसके लिए लगभग एक करोड़ रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है?"

"यात्रा-खर्च एक करोड़ रु० का नहीं, लगभग ३० लाख का ही है, वह भी राजभाषा विभाग के १९८९-९० के बजट के अंतर्गत," ऐसा रत्नाकर पांडेय का मानना है। सूत्रों के अनुसार विभाग का प्रतिवर्ष का एक निर्धारित बजट होता है। खर्च न होने के कारण इसे पिछले कई वर्षों से लौटाया जा रहा है।

राजनीतिक पहलू: प्रश्न उठता है कि फिर समिति के ही एक सदस्य (कालदाते) ने मुखर विरोध कर यात्रा क्यों स्थगित करायी? नरेशचंद्र चतुर्वेदी कहते हैं, "कदाचित बापू कालदाते अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को कठघरे में खड़ा करके यह उजागर करना चाहते थे कि देश में तो राजभाषा (हिंदी) ठीक ढंग से काम कर नहीं रही है और उसे भरपूर समर्थन-सहयोग नहीं मिल पा रहा है, फिर विदेशों में इसकी जांच क्यों करायी जा रही है? वैसे मेरी समझ में बापू कालदाते द्वारा उठायी गयी आपत्ति में राजभाषा के प्रति समर्पण कम है, राजनीतिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति अधिक है।"

अटलबिहारी वाजपेयी ने जोड़ा, "इन महाशय (कालदाते) ने विदेश यात्रा पर बावेला अवश्य मचाया है, पर देश में हिंदी के नाम पर गर्मी के दिनों में पहाड़ों और सर्दियों में समुद्र तटवाले स्थानों की यात्रा करने में कभी कोताही नहीं की।"

इस प्रकरण में मात्र बाबू कालदाते ही राजनीति के शिकार नहीं रहे। कालदाते द्वारा मामला उछाले जाने के बाद राजनीतिक अपयश से बचने के लिए वामपंथियों ने भी दौरे से अपना पल्ला झाड़ने का ताबड़तोड़ ऐलान किया। गृहमंत्री बूटा सिंह के स्थगन आदेश से भी चुनावी वर्ष में सरकार और पार्टी को विवाद अथवा अपयश से मुक्त रखने का मंशा ही उजागर हुआ है।

३ जून से पखवारे भर तक की विदेशयात्रा ३१ मई को स्थगित की जाने पर सबसे अधिक रोष दिखानेवाले इंका सांसद हैं डा० रत्नाकर पांडेय। वे इस स्थगन को 'राष्ट्रभाषा का अपमान' मानते हैं जो 'एक दर्जन इंका मुख्यमंत्रियों को अपमानित करने या बदलने' से भी ज्यादा संगीन मामला है और जिसका खमियाजा बूटा सिंह को भुगतना ही पड़ेगा। इस मामले को सड़क पर और गली-कूचों में ले जाने की धमकी दे रहे डा० पांडेय का दावा है कि समिति के एक दर्जन इंका सदस्य (मसलन वीणा वर्मा, एनसी चतुर्वेदी, बालकवि बैरागी, बंधू महतो, जे चोक्का रेड्डी, हरीश रावत आदि) उनके समर्थक हैं। यहीं विपक्षियों का यह आरोप काबिलेगौर हो जाता है कि संसद की राजभाषा समिति के अधिकांश इंका सदस्य विदेश दौरों के बहाने अपने व्यावसायिक संबंध-संपर्क बढ़ाते और लाखों के ब्योरे फिट करते हैं, हिंदी का कोई काम नहीं करते। खासकर डा० पांडेय और उनके अग्रज सुधाकर पांडेय पर तो 'हिंदी के नाम पर खुली हरामखोरी' करने के आरोप हैं और कहा जाता है कि पांडेय बंधुओं ने 'नागरी प्रचारिणी सभा' को अपनी जागीर बनाकर लूटते-खाते रहने के लिए ही इंदिराजी के बाद राजीव गांधी की शरण गही है। डा० कालदाते के समर्थक कहते भी हैं, 'वास्तव में राष्ट्रभाषा को कौन अपमानित कर रहा है, इसका निर्णय तो नागरी प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं की जांच से ही हो सकता है। जो लोग देश में हिंदी का चीरहरण कर रहे हैं, वे विदेशों में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित क्यों हैं? ऐसे लोग जब तक संसदीय राजभाषा समिति में रहेंगे, तब तक समिति के विदेश दौरों से हिंदी के हित से अधिक अहित ही होंगे।"

डा० पांडेय और उनके अग्रज सुधाकर पांडेय पर तो 'हिंदी के नाम पर खुली हरामखोरी' करने के आरोप हैं और कहा जाता है कि पांडेय बंधुओं ने 'नागरी प्रचारिणी सभा' को अपनी जागीर बनाकर लूटते-खाते रहने के लिए ही इंदिराजी के बाद राजीव गांधी की शरण गही है। डा० कालदाते के समर्थक कहते भी हैं, "वास्तव में राष्ट्रभाषा को कौन अपमानित कर रहा है, इसका निर्णय तो नागरी प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं की जांच से ही हो सकता है। जो लोग देश में हिंदी का चीरहरण कर रहे हैं, वे विदेशों में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित क्यों हैं?"

अटलबिहारी वाजपेयी के अनुसार मामला राजभाषा के सम्मान का है। विदेशों में राजभाषा का सवाल राष्ट्र के सम्मान से भी जुड़ जाता है। किंतु स्थिति यह है कि हमारे दूतावासों में कई जगह नामपट्ट तक हिंदी में नहीं होते। अपने कटु अनुभव की जानकारी देते हुए वाजपेयी ने 'माया' को बताया कि जनता शासनकाल में विदेशमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देनेवाले वे न सिर्फ पहले भारतीय नेता ही थे, बल्कि अपने भाषण का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करनेवाले भी। आज दस वर्ष बाद भी स्थिति वहीं-की-वहीं है।

राजभाषा समिति का स्थगित दौरा, नये विरोध के कारण, पुनः आयोजित होगा अथवा स्वयमेव रद्द हो जायेगा, फिलहाल कहना कठिन है। किंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रस्तावित दौरों के आयोजन व स्थगन, दोनों ही निर्णय राजभाषा की प्रगति और सम्मान से कहीं अधिक निजी राजनीतिक मंशा से प्रेरित रहे हैं। इसकी दुखद परिणति यह है कि अति प्रचार और कुप्रचार की इस रस्साकशी में राजभाषा हिंदी एक बार फिर बलि का बकरा बना दी गयी।

—रंजना कक्कड़

खैर-अलीगढ़

किसानों पर गोली क्यों चली ?

१५ जून को अलीगढ़ के खैर कस्बे में किसानों पर पुलिस की गोलीबारी की पृष्ठभूमि क्या थी ? और परिणाम क्या होंगे ?

कातिल की चौकसी : गोलीबारी वाली जगह पर गश्ती पुलिस

शामली (मुजफ्फर नगर) बिजलीघर में आग लगाने की घटना से भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने अपने दांत और पंजे दिखाने शुरू किये थे जो अब खैर (अलीगढ़) में पहुचकर सीधा पुलिस और पालिका से टकराव की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। खैर कस्बे में इसी १५ जून को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें आरोप है कि किसानों ने पुलिस अधीक्षक (देहात) की रिवाल्वर और एक कांस्टेबल की स्टेनगन छीन ली। रिवाल्वर तो लौटा दी गयी, पर स्टेनगन का पता नहीं चला। कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ गये। लेकिन दोनों ओर से १५ मिनट तक हुई गोलीबारी में पांच व्यक्ति तो घटना स्थल पर ही मर गये, एक व्यक्ति ने अलीगढ़ अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया और ६० से भी अधिक व्यक्तियों के घायल होने की बात कही जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के गांव सिसौली से जो बवंडर उठा था, वह अब धीरे-धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलता जा रहा है। चर्चा है कि अपने आंदोलन का प्रसार करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता अब हिंसक टकराव का रास्ता अपनाने लगे हैं। आरोप है कि अलीगढ़ जिले में अपने आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से भाकियू के नेता जनवरी से लेकर मई मास तक तीन दर्जन हिंसक वारदात कर चुके हैं। चुनाव वर्ष होने के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि वे भाकियू के आंदोलन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और टकराव से बचें।

भाकियू ने अपने आंदोलन को किसानों की आर्थिक मांगो से जोड़ रखा है। यूनियन के नेताओं का आदेश है कि किसान किसी भी हालत में अपना गेहूं २५० रुपए कुंतल से कम भाव पर न बेचें। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहरों और मंडियों में किसान सेना के जवान नियुक्त कर रखे हैं। आरोप है कि वे किसी को भी किसान यूनियन के खरीद केंद्र के अतिरिक्त और कहीं से गल्ला खरीदने नहीं देते। गेहूं की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध तोड़कर अन्य प्रदेशों में अपना गेहूं भेजते हैं। जहां मौका मिलता है, अफसरों और पुलिसवालो की पिटाई भी कर देते हैं। नुक्कड़ सभाएं और घेराव आयोजित करते हैं। वे सब नियमों और कायदों को तोड़कर तथा मंडी शुल्क चुंगी आदि की अदायगी किये बिना अपना गल्ला शहरों और कस्बों में ले जाकर बेचते हैं। कांग्रेस भाकियू के आंदोलन के किसी कदम में कोई अड़चन नहीं डालती, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत के साथ चल रही उच्चस्तरीय वार्ता में, वह कोई खलल पैदा नहीं करना चाहती। उसे उम्मीद है कि भाकियू का आंदोलन जितना फैलेगा, समझौता हो जाने के बाद, कांग्रेस को उतना ही लाभ होगा। कांग्रेस सरकार और प्रशासन खामोश है और भाकियू अपना प्रभाव-विस्तार करती जा रही है। खैर कस्बे की घटना प्रशासन की इसी चुप्पी और भाकियू नेताओं के बढ़ते हौसले का परिणाम थी।

घटना चक्र : खैर कस्बे में १५ जून को गोली चली। इससे पहले दो घटनाएं हुई थीं जिनसे बात इतनी बिगड़ी कि बहुत बडा गोलीकांड हो गया। भाकियू अलीगढ़ के लगभग २०० कार्यकर्ता इलाहाबाद में हुई प्रांतीय बैठक में भाग लेकर बिना टिकट अलीगढ़ लौट रहे थे। उनके एक बेटिकट साथी को पकड़कर रेलवे के अफसरों ने इटावा स्टेशन पर उतार लिया। इसके विरोध में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने चेन खींच कर ट्रेन रोक ली। वे रेलवे-लाइन पर लेट गये और दोनों ओर से ट्रेनों का आना-जाना रुक गया। रेलवे अधिकारी घबरा उठे और बाद में उन्होंने इटावा में रोके गये भाकियू कार्यकर्ता को दूसरी ट्रेन पर बिठाकर भेजा, तब कहीं जाकर वह आंदोलन खतम हुआ।

दूसरी घटना खैर की है। नगरपालिका खैर और मालीपुरा निवासी रामलाल के बीच एक भूखंड को लेकर मुकदमा चल रहा था। नगरपालिका मुकदमा जीत गयी। उसने इस भूखंड पर दो दुकानें बनवा दी। १३/१४ जून की रात को रामलाल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और उसने दुकानों को ढहा दिया। दुकानें तोड़ी जाने की सूचना मिलने पर नगरपालिका अध्यक्ष रघुकुल तिलक गढ़ ने थाने में रपट लिखा दी। इस रपट के आधार पर पुलिस रामलाल, उसके पुत्र छत्रसाल तथा चचेरे भाई रामस्वरूप को पकडकर थाने ले गयी। थाने पर रामलाल ने अपनी भूल स्वीकार कर ली तथा थाने पर ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरीशंकर आजाद की मध्यस्थता से नगरपालिका अध्यक्ष से उसने समझौता कर लिया। समझौते के मुताबिक नगरपालिका, को ढहाई गयी दुकान और बाउडरी पुन: बनवानी थी तथा उस पर होनेवाले व्यय का आधा भार नगरपालिका और आधा रामलाल को वहन करना था।

इस समझौते के बाद पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया। रामलाल ने गांव जाकर जब लोगों को समझौते की बात बतायी, तो कुछ नेता टाइप के लोग रामलाल पर समझौता तोड़ देने के लिए दबाव डालने लगे। रामलाल की मन:स्थिति बदल गयी। अगले दिन सुबह जब नगरपालिका के मजदूर, निर्माण कार्य के लिए पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद किसान यूनियन के लोगों ने उन्हें डांटकर भगा दिया, नगरमहापालिका कर्मचारियों ने तब पुलिस से सहायता मांगी। इस पर इंसपेक्टर दिलावर सिंह और सब इंसपेक्टर चौधरी भाकियू के कार्यकर्ताओं को समझाने-बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं ने दोनों पुलिसकर्मियों से न केवल मारपीट की, वरन उनके कपड़े तक फाड़ डाले।

दूसरी ओर, नगरपालिका कर्मचारियों ने मंडी स्थल पर अनशन कर रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। इस संघर्ष में पांच लोग घायल हो गये। उस दिन मामला काफी गर्म रहा। अगले दिन यानी १५ जून को सुबह से ही आसपास के इलाकों के किसानों का खैर पहुंचना शुरू हो गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए कस्बे के व्यापारियों ने उस दिन बाजारबंदी की घोषणा कर दी।

सरकारी कार्रवाई : जिलाप्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक (देहात) गुरुदर्शन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी सुबह से ही खैर में तैनात कर दी थी। लगभग चार हजार किसान टप्पल रोड पर स्थित मालीपुरा

संघर्ष की सहमति: गांवों में किसान यूनियन की बैठकों की एक झलक

जन के खिलाफ जन: किसान यूनियन से लड़ने पर आमादा खैरवासी

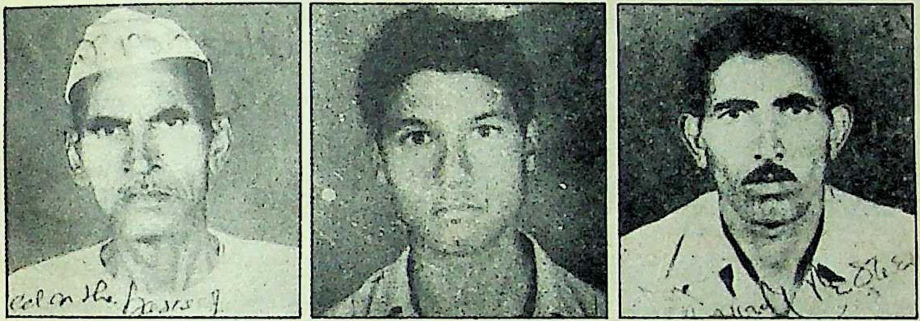

नृशंसता के नमूने: पुलिस की गोली से मरे खुशहाल, वीरेंद्र, राजवीर

के बाग में इकट्ठे हो गये और जनसभा करने लगे। इसी बीच पुलिस उपाधीक्षक हरपाल सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर सभा में पहुंचे और किसानों से सभा समाप्त कर भाग जाने के लिए कहा। इस पर किसानों में रोष फैल गया। उन्होंने पथराव कर पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया। कहा जाता है कि इसी के बाद किसानों ने खैर कस्बे में घुसकर उत्पात मचाने का प्रयास किया, तो पुलिस अधीक्षक (देहात) ने उन्हें समझाना चाहा, मगर किसानों ने उनकी रिवाल्वर छीन ली। पुलिस का आरोप है कि यह रिवाल्वर तो किसानों ने वापस कर दी, लेकिन सिपाही दलवीर सिंह से छीनी गयी स्टेनगन का कहीं पता नहीं चला। कुछ किसानों ने फिर खैर कस्बे की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को भी आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दंगाइयों के भाग जाने के बाद पुलिस ने इन लाशों को खेतों से उठाया तथा सीधे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

इस गोलीकांड में पांच किसान मौके पर ही मारे गये, जबकि एक की मृत्यु अलीगढ़ जिला अस्पताल में हुई। पुलिस ने मरनेवाले सभी छहों लोगों का अगले दिन गुपचुप पोस्टमार्टम कराया और आनन-फानन उनकी अंत्येष्टि गंगा के किनारे कर दी। मरनेवालों में भैरव सिंह, खुशहाल सिंह, नत्थू सिंह, वीरेंद्र उर्फ करुआ तथा विजेंद्र थे। एक मृतक की शिनाख्त दो दिनों बाद तक नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने इतना नृशंस व बर्बर कांड इसके पहले कभी नहीं देखा था।

पुलिस का चेहरा: पुलिस अपनी सफाई में कहती है कि उसने जो गोलियां चलायीं, उनसे सिर्फ एक व्यक्ति ही मारा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक मृतक को ही 'थ्री नाट थ्री' की गोली लगी है। बाकी चार लोगों को १२ बोर की गोलियां तथा एक अन्य को ३८ बोर की गोली (जो रिवाल्वर की होती है) लगी है। पूर्वमंत्री व विधायक राजेंद्र सिंह का आरोप है कि पुलिस का यह सारा खेल बेहद घिनौना रहा, "मेरे क्षेत्र के लोग मारे गये और मैं इनकी शिनाख्त कर सकता था, लेकिन मुझे भी मौका नहीं दिया गया। डीएम, एसएसपी ने मुझसे कह दिया कि हमने मृतकों का क्रियाकर्म कर दिया है।" राजेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए 'स्टेनगन' छीनने की कहानी गढ़ी है। वास्तविकता यह है कि पुलिस ने बहशीपन में आपराधिक कृत्य कर डाला है। इसके लिए जिला प्रशासन समेत सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध धारा-३०२ के तहत अभियोग चलना चाहिए।

बाग में हुई तीन मौतों के बारे में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह निर्ममता से की गयी मौतें थीं। विधायक राजेंद्र सिंह का कहना है कि ६५ वर्षीय वृद्ध खुशहाल सिंह के भागते समय नकली दांत नीचे गिर चुके थे। टोपी एक तरफ पड़ी थी, फिर वह हाथ जोड़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने एक न मानी और उसे गोलियों से भून दिया।

दो सगे भाइयों विजेंद्र (२६ वर्षीय) व वीरेन्द्र (१८ वर्षीय) की मौत भी इसी तरह से हुई। ये दोनों भाई यूनियन के कार्यकर्ता थे और हिरौला गांव के उमराव सिंह के पुत्र थे। दोनों यूनियन की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे और सुबह ही गांव के अन्य लोगों के साथ घर से निकले थे। इनकी मृत्यु के चश्मदीद गवाह साहब सिंह ने बताया कि पहले पुलिस की गोली वीरेंद्र के हाथ व पेट में लगी, वह जमीन पर गिर गया। खून का फौव्वारा छूटने लगा। मैं भी उसके साथ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यह देख बड़ा भाई विजेंद्र मेरे पास आया और बोला, "चलो वीरेंद्र को खींचकर ले चलें।" साहब सिंह बताता है कि हम दोनों वीरेंद्र को करीब ४०० गज तक खींचकर ले गये। थोड़ी ही देर में पुलिस की एक गोली विजेंद्र की पीठ को पार कर गयी। विजेंद्र यह कहता हुआ वहीं ढेर हो गया, "चाचा (साहब सिंह) भाग जाओ, मैं तो अब गया।" दो बेटों के जाने का सदमा सहनेवाले उमराव की आंखों से सुबह से इतने आंसू बह चुके हैं कि अब आंखें पथरा गयी हैं। वे बताते हैं कि हम जब लाश लेने गये, तो हमसे डीएम ने कहा कि तुम्हें भी बंद कर देंगे। भाग जाओ।

इस सारे घटनाक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष की भूमिका भी काफी विवादास्पद रही है। किसानों ने इससे पूर्व मेरठ और दिल्ली के बोट क्लब पर भी धरना दिया था, लेकिन कभी भी उनका रुख हिंसक नहीं हुआ। इस बार पुलिस की ज्यादती और अनावश्यक हस्तक्षेप से जो घटना घटी है, उससे भारतीय किसान यूनियन का आंदोलित होना स्वाभाविक है। बहरहाल, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने अब सरकार से आरपार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। देखना है कि सरकार टिकैत का सामना किस तरह करती है। अलीगढ़ के एक राजनीतिक नेता का कहना है कि यदि सरकार ने सूझबूझ से काम नहीं लिया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी घातक हिंसक आंदोलनों की गिरफ्त में आ जायेगा।

—लखनऊ ब्यूरो

छाया—मनमोहन शर्मा

बाल रश्मि सोसायटी

समाजसेवी संस्था पर सियासी कहर

'सांसी' होने का दंड: ६५ वर्षीय सोनी

नृशंस मारपीट: अनारी

जातीय हिंसा की शिकार: मिम्मी

जयपुर की बस्सी तहसील में १९८१. से 'बाल रश्मि सोसायटी' नामक संस्था कार्यरत है जो आपात स्थिति में फंसी हुई वेदनाग्रस्त महिलाओं की मदद करती है, साथ ही बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम चलाते हुए निराश्रित बच्चों का पालन-पोषण एवं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करती है। १९७२ में चार हरिजन बच्चों से इस संस्था ने जयपुर शहर में शिशु-गृह प्रारंभ किया था। संस्था की संस्थापक सचिव श्रीमती एलिस गर्ग आज जयपुर की कच्ची बस्तियों के साथ-साथ बस्सी तहसील के १२७ गांवों के पचपन हजार लोगों पर अपना असर रखती हैं। इस वर्ष सर्वोत्तम स्वयंसेवी संस्था के रूप में राज्य सरकार ने 'बाल रश्मि' का चयन भी किया है। इस चयन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार संस्था को पचास हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप देगी। लेकिन ऐसी समाजसेवी संस्था के लिए हमारे ही समाज के कुछ तथाकथित इज्जतदार लोग रोड़ा बने हुए हैं। उसका मूल कारण है, संस्था द्वारा सांसी जनजातियों को संरक्षण दिया जाना। समाज के ऐसे ठेकेदारों का अभी भी मानना है कि ये जनजातियां आज भी जरायम पेशा करती हैं, इसलिए इनकी मदद नहीं की जानी चाहिए। 'माया' ने उनकी समस्याओं को विगत अप्रैल '८८ के अंक में भी विस्तार से उठाया था।

बहरहाल, देश-विदेश में चर्चा का विषय बनी इस संस्था की संस्थापक श्रीमती एलिस गर्ग को ११ मई '८९ को जिस तरह से अपमानित किया गया, वह गौरतलब है। श्रीमती गर्ग उस दिन कनाडा से आये हुए शिष्टमंडल, जिसमें ओटावा विश्वविद्यालय के छात्र एवं प्रोफेसर (६ महिलाएं ४ पुरुष) तथा शास्त्री इंडोकनेडियन इंस्टीट्यूट नयी दिल्ली के अधिकारी एमएम आनद के साथ 'बाल रश्मि सोसायटी' द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देख कर लौट रही थीं। तभी बस्सी तहसील के गांव खेडी की सड़क पर ट्रैक्टरों में सवार सत्तर-अस्सी लठैतों ने उनका रास्ता रोका, श्रीमती एलिस गर्ग को थप्पड़ मारा, उनकी साड़ी फाड़ दी। शिष्ट मंडल के सदस्यों को भी धक्के-मुक्के सहने पड़े। इस हंगामे से श्रीमती गर्ग और उनके साथियों को छुटकारा तब मिला, जब खेडी गांव के पूर्व एवं वर्तमान सरपंच मांगीलाल व शंकरलाल बचाव के लिए आ पहुंचे। लेकिन फिर भी लठैत अपनी हरकतों से बाज नहीं आये। उन समाज के ठेकेदारों ने श्रीमती गर्ग और उनके साथियों को वाहन में कैद कर जयपुर-आगरा राष्ट्रीय मार्ग स्थित बेनाडा तिराहे पर श्रीमती गर्ग से सादे कागज पर दो बातें लिखवायीं और हस्ताक्षर करने को कहा। पुलिस थाना बस्सी के अधिकारी के नाम लिखी जाने वाली अप्लीकेशन में दर्ज था- "(नामजद) चार सांसियों ने हारवाडी गांव के भगवान सहाय के यहां चोरी की है और चोरी का माल अभी भी इनके कब्जे में है। मुझे (श्रीमती गर्ग) किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया।" लाठी के जोर पर लिखवायी गयी इस इबारत एवं हस्ताक्षरों को शिष्ट मंडल के अन्य सदस्य एमएम आनंद से प्रमाणित करवाया गया कि ये इबारत और हस्ताक्षर श्रीमती एलिस गर्ग के हैं।

बकौल एलिस गर्ग: एलिस गर्ग बताती हैं, "हमें इसके बाद तिराहे स्थित कल्याणजी की धर्मशाला में जाने के लिए मजबूर किया गया। वहां पर हमने देखा कि पास के गांव के सांसी पुरुष और महिलाएं भी मौजूद हैं। हमें पता चला कि इन्हें मार पड़ी थी। दो पुरुषों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे।" श्रीमती गर्ग बताती हैं, "दो घंटे बाद हमें यह चेतावनी देकर छोड़ा गया कि यदि मैं सांसियों की फिर मदद करूं या इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, तो मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर दिया जायेगा।"

सवाल उठता है कि श्रीमती एलिस गर्ग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? इस संदर्भ में बस्सी तहसील के हारवाडी गांव के एक व्यक्ति भगवान सहाय के यहां चोरी की घटना का मामला गौरतलब है। सवर्ण वर्ग के भगवान सहाय जैसे लोगों का मानना है कि सांसी जन जाति के लोग कभी चोरी करना नहीं छोड़ सकते, जबकि श्रीमती एलिस गर्ग सुधार के नाम पर उन्हें संरक्षण देती हैं। भगवान सहाय और उसके साथियों ने सांसी जन जाति के कथित चोरों से खुद ही निबटने का निश्चय किया। ११ मई को सुबह दस बजे इन लोगों ने सांसी जाति की छह महिलाओं—श्रवण की पत्नी सोनी, मेहताब की पत्नी अनारी, रामस्वरूप की पत्नी बरफी, बद्री की पत्नी प्रेम, बन्ना की पत्नी मिम्मी, बनवारी की पत्नी सुंदरी तथा दो पुरुषों—बनवारी एवं बगन्या को पड़ोस के गांव से जबरन उठा लिया। इन लोगों को बेनाडा तिराहे तक लाठियों से गोद-गोद कर लाया गया और भगवान सहाय के घर में चोरी का आरोप लगाते हुए इनकी पिटाई की गयी।

तिराहे स्थित कल्याणजी की धर्मशाला को चोरी कबुलवाने का थाना बताते हुए सांसी महिलाओं को बेइज्जत किया गया। बनवारी और बगन्या सांसी के हाथ बांध कर एक कोने में धकेल दिया गया। श्रीमती गर्ग और उनके शिष्ट मंडल को हांक कर धर्मशाला तक लाने वाले भगवान सहाय

और राम किसन अनारी को दूसरे कमरे में ले गये। आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। इस प्रयास पर एतराज करने पर उसको लाठियों से पीटा गया। उपस्थित लोगों ने कमरे में जाकर अनारी से बलात्कार के प्रयास को रोका। चोरी उगलवाने के प्रयास में वृद्ध महिला सोनी को बुरी तरह पीटते हुए उसके गुप्तांगों में लाठी डालने के प्रयास किये गये। इस बीच भगवान सहाय और उसके साथियों ने खाली कागजों पर इनके अंगूठों के निशान लिये और कहा जाता है कि श्रीमती एलिस गर्ग को 'रांड' कहते हुए उन्हें भी दुरुस्त करने की चेतावनी दी गयी।

बहरहाल, 'माया' ने सारे मामले की तहकीकात की, तो पता चला कि जो भगवान सहाय सांसियों पर चोरी का आरोप लगा रहा था, उसने ११ मई तक बस्सी थाने में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं करवायी थी। इस संबंध में थानाधिकारी का कहना है, "चूंकि चोरी की घटना के दिन घर सूना था, इसलिए चोरी का पता बाद में लगा।" ऐसे में सवाल पैदा होता है कि भगवान सहाय और उसके साथियों ने बगैर चोरी का पता हुए सांसियों पर चोरी का आरोप कैसे लगाया? बहरहाल, सांसी जाति की आठ महिलाओं और पुरुषों ने १२ मई '८६ को थानाधिकारी बस्सी को शिकायत दर्ज करवानी चाही, लेकिन थानाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उधर श्रीमती गर्ग ने जयपुर पहुंच कर महानिरीक्षक पुलिस (अपराध) को अपनी शिकायत दर्ज करवायी। उन्होंने जयपुर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को शिकायत दर्ज करने और प्रकरण की जांच करने के आदेश दिये। श्रीमती गर्ग का आरोप है कि पुलिस ने आक्रांताओं पर कुछ ऐसी हलकी धाराएं लगायी हैं कि उन्होंने घर बैठे जमानत करवा ली। दूसरी ओर, सांसी महिलाओं से बलात्कार के प्रयास और जुल्म की कथा को कबूल करने से पुलिस साफ मुकर रही है।

पुलिस की इस आनाकानी पर श्रीमती एलिस गर्ग का आरोप है, "हमारे प्रयासों से अनेक सांसी परिवारों ने अपनी अपराधपूर्ण जीवनशैली को त्यागा है।" थानाधिकारी बस्सी ने भी यह माना है कि १९८४ के पश्चात श्रीमती एलिस गर्ग के सुधार प्रभाव वाले क्षेत्र के सांसियों के खिलाफ चोरी की एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। सांसियों की बदली हुई यह जीवनशैली उन्हीं की जमात के बदनाम दलालों को नहीं रुच रही। वे नाम लेकर कहती हैं, "बस्सी तहसील के दयालपुरा गांव के भजनलाल सांसी का अन्य सांसियों के सुधर जाने से आमदनी का साधन ही खतम हो गया। इस तरह के दलालों को पुलिस मुखबिर के नाम पर तरजीह देती है और दलाल, सांसियों को हमारी संस्था से अलग होने या नतीजे भुगतने की चेतावनी देता आ रहा है।"

श्रीमती गर्ग बताती हैं कि ये दलाल विशेष रूप से उन सांसियों को पुलिस से परेशान करवाते हैं जो इनसे नाता तोड़ चुके हैं। श्रीमती गर्ग के अनुसार, "हमने पिछले दो वर्षों में ऐसी नौ घटनाओं के लिए पुलिस से शिकायत की है, पर चालान अभी तक दो के पेश हुए हैं।" वे सुधरी हुए सांसी महिलाओं और पुरुषों की ऐसी सूची दिखाती हैं, जिन्हें पुलिस ने १० से ३३ दिन तक गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाये रखा है व मारपीट की है। इस तरह के सात मामलों में श्रीमती गर्ग ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत कर निरपराध लोगों को छुड़ाया है।

श्रीमती गर्ग के सुधारवादी प्रयासों को आनन्द वन (महाराष्ट्र) के बाबा आमटे ने १८ मार्च '८६ को स्वयं देखा था। उन्होंने बाल-गृह में रखी पुस्तिका में टिप्पणी दर्ज की है—"एक विशाल मातृत्व का प्रत्यक्ष दर्शन खेड़ी (बस्सी तहसील) के बाल रश्मि सोसायटी में हमने किया। एलिस जैसी मां जिनको प्राप्त हुई है, उनका भविष्य उज्ज्वल है।" इसी तरह भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग के अध्यक्ष भीखा भाई ने भी इस क्षेत्र में बाल रश्मि का कार्य देखकर उसे शानदार व अनुकरणीय बताया है। समाज के इन महत्वपूर्ण लोगों की वाहवाही ने रूढ़िवादी समाज और स्थानीय राजनेताओं को चौंका दिया है। उन्हें लगने लगा है कि चुनाव वर्ष में श्रीमती गर्ग इस क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता को भुना सकती हैं। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक स्थिति रखते हैं और श्रीमती गर्ग उनकी एक मात्र संरक्षक हैं। ऐसे में कांग्रेस-इ के वर्तमान विधायक भाजपा और जनता दल के संभावित उम्मीदवार सभी इस प्रयास में हैं कि श्रीमती गर्ग या तो उनकी पक्षधर बन जायें अथवा क्षेत्र में अपनी सुधार गतिविधियां बंद कर दें। श्रीमती गर्ग से जब 'माया' ने उनके राजनीतिक इरादों के संबंध में जानकारी चाही, तो उनका कहना था—"जिन लोगों की शराब मैं छुड़ा रही हूं, उन्हीं को शराब पिला कर वोट मांगने की राजनीति से मैंने पहले ही तोबा कर लिया है। मैंने विभिन्न दलों के राजनेताओं से स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी इस क्षेत्र में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है।" पर महत्वाकांक्षाओं के छुपे सपने भांपने का दावा करनेवाले राजनीतिज्ञ इस सपाटबयानी को नहीं स्वीकारते।

मसीहा पर आरोप: श्रीमती एलिस गर्ग

श्रीमती गर्ग पर आरोप: श्रीमती गर्ग को फंसाने के लिए सांसी जाति के पुलिस दलाल बहुत चालें चल रहे हैं। पुलिस मुखबिर भजनलाल ने सांगानेर पंचायत समिति के मदाउ गांव के अपने मित्र बनवारी के सहयोग से अपनी २० वर्षीय लड़की रेखा द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इस रिपोर्ट में आरोप है कि श्रीमतो गर्ग ने उक्त लड़की को पंद्रह दिनों तक जबरन अपने फार्म (आश्रम) पर रखा जहां उसके साथ कई व्यक्तियों ने बलात्कार किया। रेखा ने अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया है कि उसे जबरन एलिस गर्ग के लोग उठा ले गये। श्रीमती गर्ग ने उसे मारा-पीटा और बस्सी तहसील के हसाडा गांव की केसरा मीणा की ढाणी में कैद कर लिया, जहां उससे अपहरण करनेवालों ने लगातार बलात्कार किया। उसके अनुसार वह एक दिन शौच के बहाने से निकल भागी और अदालत में उपस्थित हुई है।

जबकि श्रीमती गर्ग ऐसी किसी लड़की को जानने से साफ इनकार करती हैं। उन्होंने बताया कि लड़की की उम्र थाने में १४ वर्ष लिखायी गयी है, जबकि वह बीस वर्ष की है। उसे अविवाहित बताया गया है, जबकि उसका विवाह खटवाडा गांव के धानीया के बेटे बाबू से हो चुका है। चार साल की इस विवाहिता ने जिस तरह से अदालत में बयान दिये हैं, उसे श्रीमती गर्ग आश्चर्यजनक नहीं मानतीं। वे कहती हैं कि सांसी दलाल भजनलाल अपने भय से बिगड़े हुए सांसियों से कुछ भी कहलवा सकता है।

श्रीमती गर्ग इन साजिशों के लिए किसी एक राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगाना चाहतीं। वे कहती हैं कि ऐसा करके ही विकास कार्यक्रमों की जगह झूठे आरोपों का जवाब देने में वक्त गंवाना पड़ेगा। फिर भी श्रीमती गर्ग को अपमानित करने वाली घटना के बाद १५ मई को भाजपा समर्थकों ने उसी तिराहे पर बस्सी के ग्रामीणों की सभा की, जहां श्रीमती गर्ग को अपमानित किया गया था। इस सभा का विवरण भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि बीएल दुसाद ने अखबारों को देते हुए बताया कि बस्सी तहसील के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल विपक्ष के नेता भैरोसिंह शेखावत से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बस्सी तहसील क्षेत्र में आये दिन सांसी जाति के लोग चोरियां करते हैं। चोरियों का पता लगने पर पकड़े सांसियों को 'बाल रश्मि सोसायटी' भानसर खेडी की संचालिका श्रीमती एलिस गर्ग छुड़ा लेती हैं और लोगों को उनका माल वापस नहीं मिलता।

इन आरोपों-प्रत्यारोपों के बावजूद राज्य सरकार खामोश है जो इस बात का संकेत है कि राजनीति के निहित स्वार्थ किसी पवित्र उद्देश्य को अलग से परखने का माद्दा नहीं रखते। बाबा आमटे को भले ही श्रीमती गर्ग में पवित्र मां नजर आती हो, पर राजनेताओं को वें केवल अपना प्रतिद्वंद्वी नजर आती हैं।

छाया: गोपाल संगर

—ओम सैनी

मंत्रिमंडल विस्तार

सत्ता का पुनर्वितरण

राजस्थान के असंतुष्ट कांग्रेसियों की मांग थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की उनके पदों से छुट्टी कर दी जाये। कांग्रेस आलाकमान ने माथुर को तो नहीं, अशोक गहलोत को कांग्रेस-अध्यक्ष पद से जरूर हटा दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जो रुतबा दे दिया गया है, उससे क्या असंतुष्टों का असंतोष और भड़क उठेगा ?

ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में राजीव गांधी विपक्ष के साथ-साथ कांग्रेस-इ के नाखुश नेताओं को सबक सिखाने के लिए विधानसभा के मध्यावधि चुनाव का रास्ता अपनायेंगे। इस धारणा के पीछे वे सब उपलब्धियां थीं जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत चुनावों और उपचुनावों में नाखुश नेताओं व विपक्ष के एकजुट होने की कोशिशों के बावजूद हासिल की थीं। लेकिन राजीव गांधी ने मध्यावधि चुनाव का विकल्प चुनने के बजाय प्रदेश कांग्रेस-इ के अध्यक्ष को बदलने और माथुर-मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का जो रास्ता अपनाया है, उसे असंतुष्टों के सामने आत्मसमर्पण की संज्ञा दी जा रही है।

राजस्थान के असंतुष्टों की लगातार यह मांग रही थी कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अगर तुरंत उनके पदों से नहीं हटाया गया, तो राजस्थान प्रदेश से आनेवाले चुनाव में कांग्रेस साफ हो जायेगी। असंतुष्ट कांग्रेसियों का नेतृत्व इस मामले में पूर्वमुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और सांसद नवल किशोर ने शुरू किया था। छह माह की इस कवायद में प्रारंभ में पंद्रह लोग थे, लेकिन बाद में जाकर इनकी संख्या तीस हो गयी। जोड़तोड़ की इस मुहिम में पूर्व गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सीपी जोशी सरकार एवं संगठन के साथ हो लिये, वहीं पूर्वमुख्यमंत्री एवं मंत्री रहे हीरालाल देवपुरा नाखुश नेताओं से जा मिले। आलाकमान की रणनीति से बाद में जोशी को असम का राज्यपाल बनना पड़ा, तो अनुसूचित जाति के पूर्वमुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। इसी तरह सांसद नवल किशोर को निर्णायक स्थितियों के दिनों में मास्कों भेजकर असंतुष्टों को नेतृत्वहीन करने की राजनीति चलायी गयी।

परंतु असंतुष्ट नेता जब आसपास के विपक्षी दलों पर नजर डालने लगे थे, तभी फैसला हुआ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद अशोक गहलोत को बदला जायेगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि कुछ असंतुष्ट नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा को बनाया जायेगा।

देवपुरा प्रसंग: ज्ञात सूत्रों के अनुसार हीरालाल देवपुरा को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पांच जून को देर रात की मुलाकात में कह दिया था, "आप जाकर प्रदेश अध्यक्ष का काम संभालें और सबको साथ लेकर चलें।" देवपुरा तुरंत जयपुर लौटे, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से उनके अध्यक्ष बनने के निर्णय की पुष्टि सात जून तक टलती रही। देवपुरा आलाकमान के इस रवैये से हतप्रभ थे, तो अशोक गहलोत अपने सहयोगियों को सहयोग के लिए धन्यवाद-पत्र भेजने में मशगूल थे। बहरहाल, सात तारीख की संध्या को आलाकमान ने दूरदर्शन के माध्यम से अपने निर्णय की पुष्टि की, लेकिन देवपुरा का चित्र दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया। इस बीच [illegible] आलाकमान इस सवाल पर विचार करता रहा कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत द्वारा संगठन में खड़ी की युवाओं की फौज पर बदलाव की क्या प्रतिक्रिया होगी ? देवपुरा को तय करने के बाद अशोक गहलोत को जयपुर में युवाओं को शांत करने और नयी रणनीति से अवगत कराने के लिए भेजा गया था। जब गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त हो गये, तभी आलाकमान ने देवपुरा के नाम की पुष्टि की। इसी बीच यह भी तय हुआ कि गहलोत-समर्थक मंत्रियों और संगठन में मनोनीत युवा नेताओं को

असंतोष का शमन: हीरालाल देवपुरा और शिवचरण माथुर गले मिलते हुए, साथ में अशोक गहलोत

नहीं छेड़ा जायेगा, भले ही कुछ नये लोग और जोड़ दिये जायें। घोषणा से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नये मंत्रियों की सूची तैयार हुई और तय हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का मनोनयन व मंत्रिमंडल का विस्तार एक साथ हो।

गौरतलब यह है कि इस सारे मामले में आलाकमान और अशोक गहलोत सब कुछ तय करते रहे। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भी यह पता नहीं था कि उन्हें आठ तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। स्वयं मुख्यमंत्री ने 'माया' से बात करते हुए इस तथ्य की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सात जून को माउंटआबू पहुच गये थे, जबकि नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवपुरा ने संवाददाताओं से बात करते हुए दस जून को पद भार ग्रहण करने की बात कही थी। बहरहाल, अशोक गहलोत लगातार दिल्ली के सम्पर्क में थे। मुख्यमंत्री को आलाकमान का संदेश देर रात में मिला, जिसमें तय था कि कौन-कौन, किस-किस विभाग के मंत्री बनाये जायेंगे और देवपुरा कितने बजे पदभार ग्रहण करेंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार : बहरहाल, सोलह माह पुराने शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल में ग्यारह नये मंत्री शामिल किये गये, जबकि दो मंत्री हटा दिये गये। नये मंत्रियों में चार कैबिनेट स्तर के, छह राज्यमंत्री और एक उपमंत्री शामिल हैं। सहकारिता मंत्री हनुमान प्रभाकर को अपनी चर्चित छवि के कारण और खान राज्यमंत्री लक्ष्मण सिंह को खान आवंटन विवाद के उच्च न्यायालय में पहुंचने के कारण पदमुक्त कर दिया गया है। आठ जून को आयोजित इस शपथ-ग्रहण समारोह में सांसद अशोक गहलोत को सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी। गहलोत के बाद श्रीमती कमला, गुलाब सिंह शक्तावत और रामसिंह विश्नोई ने शपथ ली। राज्यमंत्री के रूप में दीपचंद राठौड़, भरतलाल मीणा, भैरूलाल मीणा, महेन्द्र कुमार परमार, सुजान सिंह यादव और हीरालाल इंदौरा को शामिल किया गया, जबकि युवा विधायक ललित भाटी को उपमंत्री के पद की शपथ दिलवायी गयी।

दस नये मंत्रियों के शामिल हो जाने से राजस्थान मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या २२ से बढ़कर ३२ हो गयी है। अगर संसदीय सचिवों को इसमें गिना जाये, तो तीन संसदीय सचिवों के मिलने से संख्या ३५ सदस्यीय हो जाती है। राज्य में वर्तमान मंत्रिमंडल संख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा मंत्रिमंडल है। इसके पूर्व १९६७ में सुखाड़िया मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या ४२ रही है। उस समय राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या १८२ हुआ करती थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक ९२ थे। संविद सरकारों के दौर में व कांग्रेस विरोधी लहर में सुखाडिया मंत्रिमंडल ने अपनी सरकार बनाने के लिए देश के पहले 'आयाराम' की मदद से सरकार गठित की तथा बाद में भी आयारामों के लिए द्वार खुले रखे।

भय की रणनीति : वर्तमान शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल के व्यापक विस्तार के पीछे यह भय विद्यमान था कि असंतुष्ट विधायक कांग्रेस-इ की सरकार को प्रांत में गिरा सकते हैं। इसी भय को आधार मानकर कांग्रेस-इ के मजबूत संगठनवाले प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की परिकल्पना की गयी थी। बहरहाल, आलाकमान ने इस मामले में चुनाव जोखिम के बजाय सुखाड़िया शैली में मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता चुना। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर इसे चुनाव वर्ष में सभी वर्गों एवं जिलों को प्रतिनिधित्व देनेवाला मंत्रिमंडल बताते हैं। उनका दावा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारह मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में लेकर उन्होंने राजस्थान में पहली बार ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन जातियों को दिया है। वैसे, माथुर मंत्रिमंडल में जोधपुर और उदयपुर संभाग के लोगों का बोलबाला है।

इस विस्तार का दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें नाखुश नेताओं को वह लाभ नहीं मिला, जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। मसलन, असंतुष्टों की मुहिम में विशेष सक्रिय रहनेवाले पूर्वमंत्री रामदेव सिंह महरिया, रामपाल उपाध्याय, श्रीमती जकिया इनाम, छोगाराम बाकोलिया को अलग रखा गया है। इसी तरह राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केसी विश्नोई, विधायिका श्रीमती नीलिमा शर्मा, रतनलाल ताम्बी जैसों को गौण कर दिया, जबकि अपनी पुत्री के 'प्रेम-संबंधों' को लेकर बदनाम हुए पूर्वमंत्री रामसिंह विश्नोई को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है।

इस विस्तार के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल में तीन खेमे साफ नजर आते हैं—एक खेमे में मुख्यमंत्री समर्थक मंत्री हैं, जबकि दूसरे खेमे में गहलोत समर्थक हैं और तीसरे खेमे में असंतुष्टों में से आये मंत्री हैं। इन खेमों में निर्णायक स्थिति अशोक गहलोत के साथ है। लग यह रहा है कि आलाकमान गहलोत खेमे अथवा गुट को हर जगह असरदार बनाकर राजस्थान की बागडोर धीरे-धीरे अशोक गहलोत को सौंपना चाहता है।

दिलचस्प दृश्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में उस समय भी देखने को मिले, जब वर्तमान मंत्री अशोक गहलोत अपना अध्यक्ष पदभार हीरालाल देवपुरा को सौंप रहे थे। इस अवसर पर मौजूद मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने माना कि सांसद अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस में युवकों की ऐसी फौज खड़ी की है जो आज तक नहीं बनी थी। ठीक इसी भाषा में हीरालाल देवपुरा ने मुख्यमंत्री की बात की पुष्टि कर दी। निश्चित रूप से इस स्थिति में नाखुश नेताओं से सवाल किया जा सकता है कि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इतने सक्षम थे, तो असंतुष्ट नेता उन्हें बदलने की मांग क्यों कर रहे थे?

'माया' ने इस संदर्भ में बातचीत के लिए नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा से वक्त मांगा। उन्होंने वक्त दिया भी, लेकिन जब सवालों में उक्त सवाल को देखा, तो साक्षात्कार देने से मुकर गये। 'माया' ने याद दिलाया कि यह सवाल तो अब हर कोई पूछेगा, तब आप क्या जवाब देंगे? प्रदेश अध्यक्ष का कहना था—"आप लिख दीजिए कि मैंने मौन धारण कर लिया।" बहरहाल, राजस्थान में कांग्रेस सरकार व संगठन में हुआ यह परिवर्तन मतदाताओं के बीच कोई नया असर पैदा करने के बजाय उनके तिकड़मी होने के स्वरूप को ही बल देगा। दूसरी तरफ, विपक्ष के लिए यह एक और मौका होगा, जिसमें वह साबित कर सके कि कांग्रेस को स्वयं अपनी साख पर विश्वास नहीं है।

—ओम सैनी

गहलोत का वर्चस्व : नये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा के साथ अशोक गहलोत

छाया : गोपाल संगर

अनोप मंडल

सांप्रदायिकता का नया चेहरा

गत ३१ मई को गृहमंत्री बूटा सिंह के चुनाव क्षेत्र सिरोही शहर के पास जांवाल गांव में हिंदू-मुस्लिम फसाद हो गया था, जिसमें दो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके पूर्व भी सिरोही जिले के आसपास पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज तथा पाली में भी उक्त दोनों कौमों के कट्टरपंथी छिटपुट फसाद करा चुके हैं, लेकिन इन इलाकों में सांप्रदायिकता का जो सर्प जैन समुदाय विशेष के लोगों को जब-तब डसता रहता है उसका हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता मे कोई संबंध नहीं। उसका स्वरूप अजीबोगरीब है। कहा जाता है कि पीढ़ियों से बनियों की सूदखोर व्यवस्था के खिलाफ चली आ रही घृणा इस क्षेत्र में जैन समुदाय के खिलाफ आक्रोश के रूप में फूट पड़ती है।

१९८१ में तो सिरोही के पास कोलारगढ़ में आगजनी और हमले की वारदात हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व पिंडवाड़ा तहसील में तो जैनियों का सामाजिक बहिष्कार तक हुआ था। उन्हें सब्जी बेचना, उनका आटा पीसना और उन्हें दूध तक देना बंद कर दिया गया था, जिसके कारण जैन समाज को तब पालनपुर (गुजरात) से अपने लिए सामान मंगाना पड़ा था। रोचक तथ्य यह है कि जैन समुदाय के प्रति विद्वेष की यह आग पाली, सिरोही और जालौर जिले तक ही सीमित है। जब यहां के कुछ खास वर्गों के लोग नारा लगाते हैं—'हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई, बनिया कौम कहां से आयी' तब बनिया शब्द से उनका अर्थ जैनियों से ही होता है। यहां के जैनियों को आशंका है कि एक बार फिर से यहां उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है और यदि सरकार सावधान नहीं हुई, तो यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

जैन प्रवेश निषिद्ध : अनूप स्वामीजी महाराज की झूंपड़ी

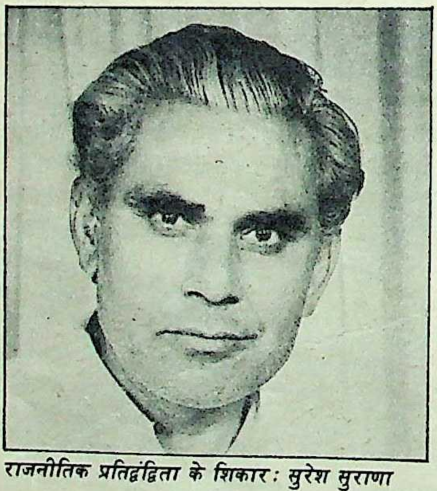

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के शिकार : सुरेश सुराणा

अनोप मंडल की गतिविधियां : जैन समाज के लोग इस विद्वेष को फैलाने के लिए इस क्षेत्र की एक धार्मिक संस्था अनोप मंडल को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस संस्था के संस्थापक बाबा अनोपदास थे जो पढ़े-लिखे नहीं थे। ब्रिटिश सेना के एक सिपाही की हैसियत से वे सोवियत रूस के उजबेक इलाके में काफी समय तैनात रहे। तब वहां साम्यवाद का तूफान आया हुआ था औरं महान सोवियत क्रांति हो चुकी थी। वहां उन्होंने धनिकों के विरुद्ध सर्वहारा के संघर्ष को देखा था। अपने इलाके की गरीबी से वे परिचित थे और यह भी जानते थे कि बनिये महाजनी और सूदखोरी के जरिए गरीब और देहाती लोगों का शोषण कर रहे हैं। सिरोही में उन दिनों बनिया वर्ग में ज्यादातर जैन थे और आबू में अग्रवाल। अनोपदास ने बनियों के खिलाफ आग उगलना शुरू किया। बनियों के ख्रिलाफ जनमानस बनाने के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि वे रावण और हिरण्यकश्यप हैं और जादू से अकाल, महामारी और भुखमरी पैदा करते हैं तथा उन्होंने असली धर्मग्रंथों के बजाय जाली किताबें बना दी हैं। उनका कहन्ना था कि पूरे संसार को 'एकजुट' होकर इनके 'राक्षसी पाप' से लड़ना चाहिए। बनियों के खिलाफ जगत के कल्याण के लिए उन्होंने 'जगत हितकारिणी पुस्तक' लिखी। जिस पर १९५६ में प्रतिबंध भी लगा, लेकिन शोषण के शिकार होते रहे गिरासिया, सुथार व सुनार आदि आदिवासी एवं जनजातियों के लोगों को वे अपने मसीहा नजर आने लगे और उनकी पुस्तक 'जगत हितकारिणी' उनके लिए गीता बन गयी। सिरोही शहर के अस्पताल के पास अनोप मंडल संस्था का मुख्यालय है, जहां इलाज के लिए आनेवाले लोगों को कुछ दिनों के लिए ठहरने का आश्रय मिल जाता है। अनोप मडल एक विचित्र संगठन है। इस सस्था का न तो कोई संविधान है और न ही यह पंजीकृत है। संत अनोपदास के शिष्य भाविक कहलाते हैं। बनिये के रूप में उन्हें जैनी ही नजर आते रहे और उनके विरुद्ध पिछड़े वर्ग में पीढ़ियों से व्याप्त घृणा का परिणाम यह हुआ कि जहां-जहां अनोपदासजी की झूंपड़ियां (मंदिर) स्थापित हैं, वहां जैन परिवार नजर नहीं आते। लेकिन यह अजीब विरोधाभास है कि आजादी के पहले भील और गरासिया जनजातियों को एकजुट कर जिस व्यक्ति ने 'एकी आंदोलन' के जरिए मेवाड़ और सिरोही रियासतों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया व ३० वर्षों तक जेल की सजा काटी, वे मोतीलाल तेजावत जैन ही थे, जिन्हें जनजातियों के लोग भगवान का एकलिंग अवतार मानते थे। तब तेजावत के साथ शोषण के विरुद्ध इस लड़ाई में जैन समुदाय भी पूरी तरह एकजुट था। लेकिन विडंबना है कि आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्षरत अनोप मंडल की गतिविधियां आजादी के बाद सिर्फ जैन समाज को ही निशाना बनाने लगीं।

जैन-विरोध क्यों ? : दरअसल, कहा जाता है कि इस शताब्दी के तीसरे दशक में बाबा अनोपदास की मृत्यु के बाद अनोप मंडल का सर्वेसर्वा बना हरचंद सोनी ने जैन-विरोधी विद्वेष को खास तौर से हवा दी। सोनी खुद सूदखोर महाजनी व्यवस्था का शिकार हुआ था। मूल और ब्याज अदा करने के बावजूद उसका ऋण सुरसा की तरह बढ़ा। यहां तक कि उसका घर नीलाम हो गया। संयोग से लेन-देन जिस महाजन के साथ था, वह भी जैन समाज का था।

हरचंद सोनी बदले की आग में झुलसता हुआ अनोप मंडल के माध्यम से जैन समाज के लिए आग उगलने लगा। पिछड़े एवं जनजाति के लोगों में पहले से पैदा नफरत को उसने अपने 'झूलनों' (दोहों) से और बढ़ाया। मसलन, उसने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में यह प्रचार करना शुरू किया कि जैन मुनि पानी को बांध देते हैं, जिससे बरसते मेघ खामोश हो जाते हैं। बताया जाता है कि सोनी के उद्‌भव के साथ ही अनोप मंडल का कार्य केवल जैनविरोध रह गया। अनोप मंडल से जुड़े लोग जैनियों को अछूत मानने लगे। जैन साधुओं का इस क्षेत्र में विचरण एक समस्या बन गयी। बरसात के मौसम में चातुर्मास के लिए ठहरे जैन मुनियों को दैनिक निवृत्तियों के लिए गांव से बाहर निकलने पर अनोप मंडल के सदस्य नियोजित तरीके से परेशान करने लगे।

राजनीति की भूमिका : आठ वर्ष पूर्व सिरोही जिले के कोलारगढ आंबेश्वर क्षेत्र में चातुर्मास कर

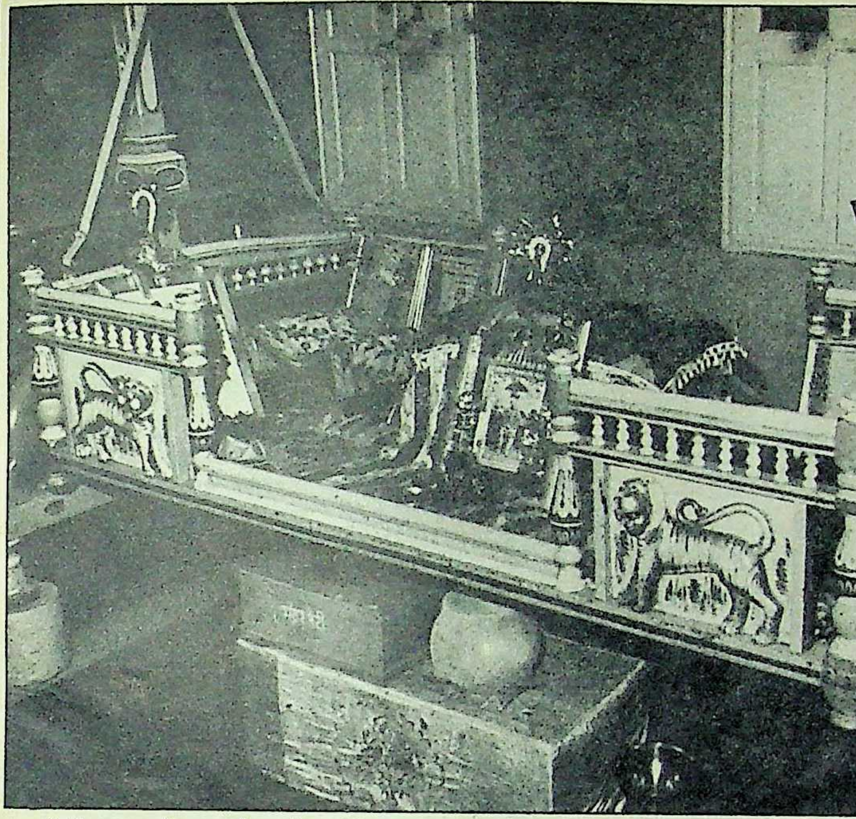

पालने में बाबा अनोपदास की तस्वीर। नीचे दान पात्र

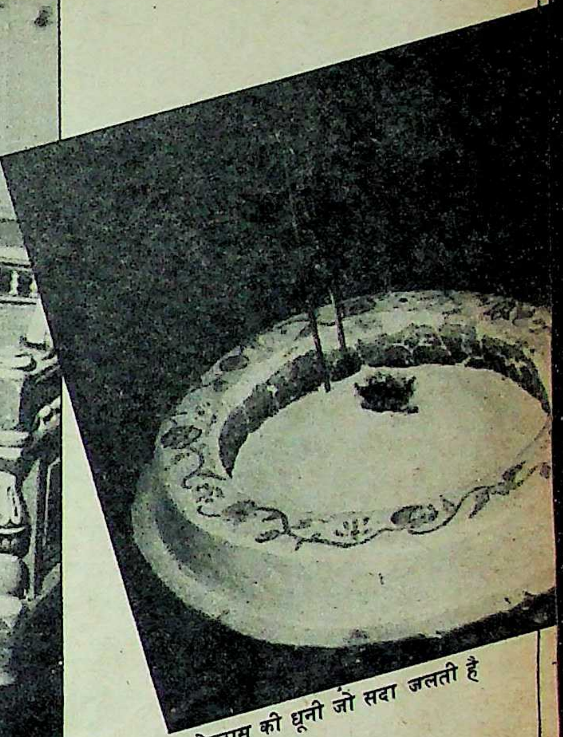

अनोपदास की धूनी जो सदा जलती है

रहे जैन मुनि रोहित विजय इसी जैन-विरोध का शिकार हुए थे। वर्षा समय पर न होने के लिए गांववालों ने उनकी पिटाई कर दी थी। पुलिस ने अनोप मंडल के जिन कार्यकर्ताओं को उस समय गिरफ्तार किया, उन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन रोचक तथ्य यह है कि शोषण के विरुद्ध संघर्षरत अनोप मंडल को शोषण का प्रतीक समझे जानेवाले सामंतों का भरपूर सहयोग मिलने लगा। जानकार लोग बताते हैं कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उठा प्रजामंडल का आंदोलन जब रियासती जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाने लगा और ब्राह्मण व जैन समाज के लोग उसके अगुवा बनने लगे, तब सामंती तत्वों ने अनोप मंडल के माध्यम से अपना बचाव शुरू किया। चर्चा यहां तक है कि सिरोही के सामंती परिवार ने ही ६५ वर्ष पूर्व बंबई के वेंकटेश्वर प्रेस में अनोपदास की पुस्तक 'जगत हितकारिणी' के प्रकाशन में सहयोग दिया था और अनोप मंडल के लिए भवन उपलब्ध करवाने में भी सिरोही राजपरिवार ने विशेष दिलचस्पी दिखायी थी। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जिला प्रमुखी का चुनाव हारे पूर्व जनता पार्टी के शहर-अध्यक्ष सुरेश सुराणा ने तो दावे के साथ यहां तक कहा कि जैन होने की वजह से वे शिकस्त खा गये। उनका कहना है, 'जनता पार्टी के ४० राजपूत सरपंच हैं, लेकिन एक ने भी मुझे वोट नहीं दिया। ये सब लोग अनोप मंडल से जुड़े हैं।' उनका आरोप है कि सिरोही का राजघराना अनोप मंडल की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। सुराणा का यह भी दावा है कि राज्य सरकार ने जब गुप्तचर विभाग से जांच कराई, तो रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनोप मंडल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सिरोही राजघराने के राजकुमार रघुवीर सिंह को दोषी पाया गया था। रघुवीर सिंह खुद दस वर्ष पूर्व संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जिला प्रमुखी का चुनाव हार चुके हैं। राजघराने के सूत्रों का कहना है, "यदि अनोप मंडल में यहां के चुनाव की जीत-हार को प्रभावित करने की ताकत होती, तो रघुवीर सिंह तब क्यों हारते ?"

यह एक रोचक तथ्य है कि बनियों के शोषण के खिलाफ जेहाद छेड़नेवाले बाबा अनोपदास का असर सिर्फ सिरोही जिले और इसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित है। इस इलाके के बाहर तो उनका नाम तक कोई नही जानता। संत परंपरा में उनके नाम का उल्लेख नहीं होता। यहां तक कि गोरखपुर से प्रकाशित 'कल्याण' के 'संत परंपरा' विशेषांक में उनका जिक्र नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि जिस सिरोही क्षेत्र में अनोप मंडल पिछली अर्धशताब्दी से शोषण के खिलाफ अलख जगा रहा है, वहां के पिछड़ेपन का आलम यह है कि पांच तहसीलों और ५१३६ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित ५ लाख, ४२ हजार की आबादीवाले सिरोही शहर तक अभी रेल नहीं पहुंची है। आबादी का ४० प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है। लेकिन कुछ गांवों में तो आज भी पिछड़ी जाति के लोगों को ठाकुरों के घर के सामने से गुजरने पर सिर पर जूतियां रखकर गुजरना पड़ता है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि इस इलाके के जैन समृद्ध हैं। अब वे लोग व्यापार के अलावा शिक्षा, वकालत, सरकारी सेवा एवं चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हो रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि उन्होंने अपने तीर्थंकरों के आलीशान मंदिर बनवाने में तो खुलकर पैसा खर्च किया, लेकिन क्षेत्र के गरीब लोगों के आर्थिक उन्नयन में, उन्होंने अपनी कोई भूमिका नहीं तलाशी। ऐसी स्थिति में इस इलाके के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों में समृद्ध जैन समुदाय के खिलाफ यदि आक्रोश पनपता है, तो यह अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि वोट की राजनीति कुछ भी करा सकती है।

सिरोही के जिला प्रशासन का मानना है कि अनोप मंडल की गतिविधियां गैरकानूनी हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उपजिलाधीश बीएस सिंघल के अनुसार, अब स्थितियां सुधर रही हैं और सौहार्द धीरे-धीरे लौट रहा है, लेकिन अनोप मंडल के जैन-विरोध का आज भी आलम यह है कि 'माया' प्रतिनिधि के बारे में यह जानने पर कि वह जैन है, उसे अनोप मंडल की झूंपड़ी (मंदिर) में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस क्षेत्र के भयभीत जैनियों का मानना है कि भीतर-ही-भीतर जैन-विरोध की चिनगारी सुलग रही है, जो राजनीति और सामंतवाद की हवा पाकर कभी भी धधक सकती है।

—भुवनेश जैन, ओम सैनी

छाया : प्रताप सिंह

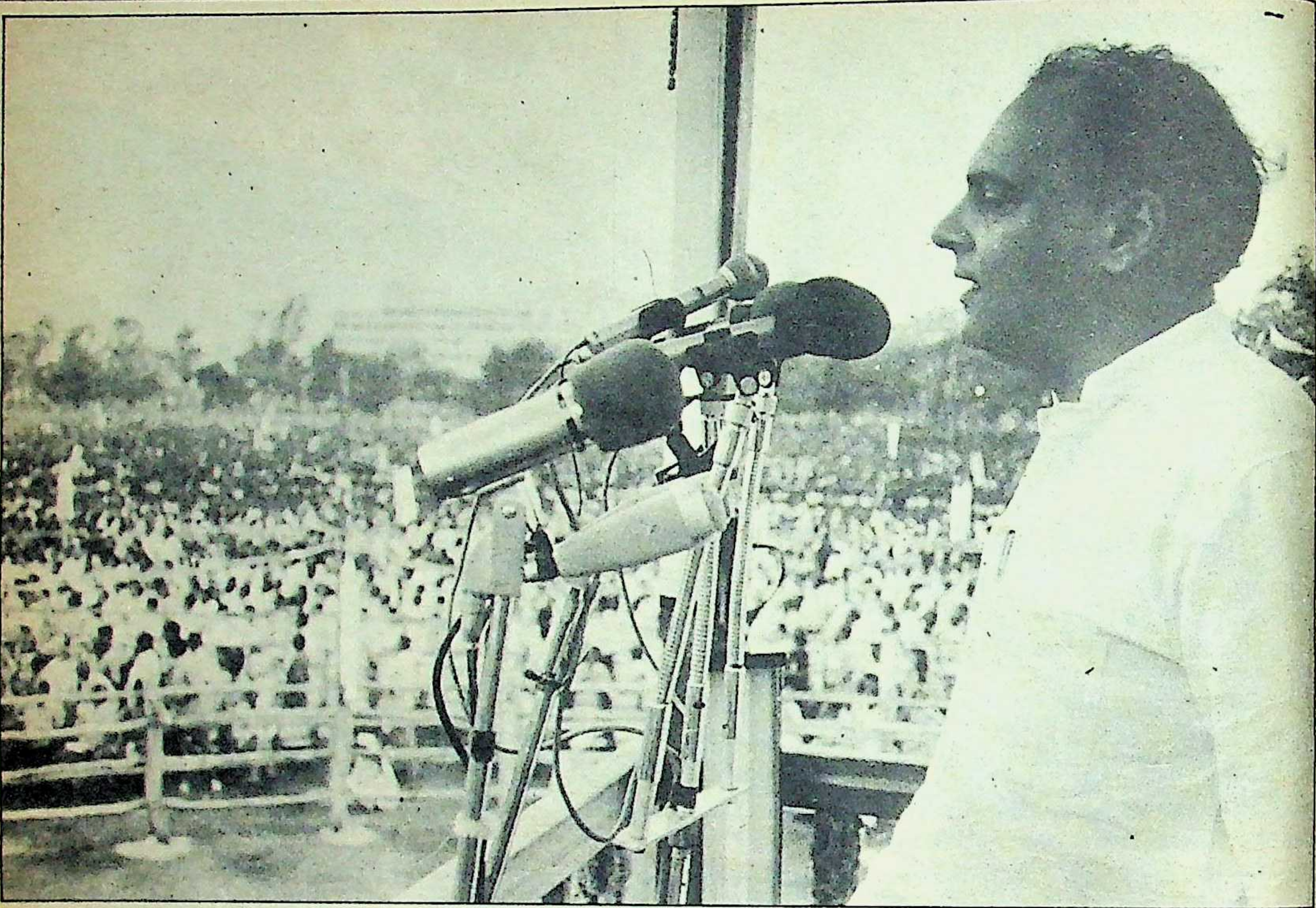

चुनाव तैयारियों का शंखनाद : पटना की आमसभा में राजीव गांधी

सत्येंद्र बनाम जगन्नाथ बनाम तारिक

आपसी टांगखिंचाई चालू आहे !

१५ जून को पटना में प्रधानमंत्री की आमसभा क्या हुई कि मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और बिहार इंका अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र के बीच जो शीतयुद्ध चल रहा था, वह खुलकर सामने आ गया। क्या सत्येंद्र व जगन्नाथ में ठन चुकी है ? पूर्व इंका अध्यक्ष तारिक अनवर जगन्नाथ के प्रति क्यों उग्र हैं ? बिहार की इंकाई राजनीति का जायजा :

बात १६ जून की है। सुबह-सुबह बिहार के मुख्य सचिव एयू शर्मा फोन पर बुरी तरह परेशान थे। वे बार-बार सफाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री के पटना-कार्यक्रम की तैयारी में तो उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी थी, फिर भी अगर कहीं कुछ चूक हो गयी है, तो इसकी जांच वे सख्ती से करवायेंगे। मुख्य सचिव शर्मा फोन पर यह सफायी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र को दे रहे थे। दरअसल, जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें फोन करके कहा था कि वे उन्हें प्रधानमंत्री के पटना-कार्यक्रम के दौरान बरती गयी प्रशासनिक लापरवाही के बारे में एक कड़ी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र की इस बात से शर्मा हतप्रभ थे। इसलिए जब चेतावनी देकर जगन्नाथ ने फोन रखा, तो बौखलाकर शर्मा ने फौरन पटना के जिलाधिकारी, बिहार के जनसंपर्क निदेशक सहित उन सभी अधिकारियों को फोन कर तत्काल कैफियत देने को कहा, जिन पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तैयारी का जिम्मा शर्मा ने सौंपा था। शर्मा की इस आकस्मिक नाराजगी से वे सारे अधिकारी भी सकते में आ गये थे और साथ ही चकित भी थे, क्योंकि १५ जून को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की आमसभा के बाद शर्मा ने ही उन सभी अधिकारियों को बेहतर तैयारी के लिए शाबाशी दी थी। पर बात यहीं खतम नहीं हुई। उसी शाम जगन्नाथ मिश्र ने कई अखबारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बयान भी दे डाला कि प्रधानमंत्री की आमसभा में लाउडस्पीकर भी ठीक से नहीं लगाये गये थे। इसलिए आमसभा में लोग प्रधानमंत्री का भाषण ठीक से नहीं सुन सके थे। जगन्नाथ मिश्र ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले की वे जांच करवाकर ही दम लेंगे। बहरहाल, इस प्रकरण से नौकरशाहों में स्वाभाविक रूप से अफरातफरी मची हुई थी, पर राजनीतिक पंडित उन निरीह नौकरशाहों की दयनीय स्थिति पर बिहंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जगन्नाथ प्रशासनिक विफलता की बात उठाकर क्या कहना चाहते हैं। राजनीतिक तीरंदाज भांप चुके थे कि जगन्नाथ परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह पर चोट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री की आमसभा के आयोजन का सारा श्रेय सिर्फ उनके हिस्से आये और यह धारणा कायम हो कि जगन्नाथ ने गांधी मैदान में लाखों की भीड़ तो अपने दम पर जुटा दी, पर सत्येंद्र नारायण सिंह की प्रशासन पर इतनी भी पकड़ नहीं थी कि आमसभा हेतु लाउडस्पीकर और पोस्टर जुटवा सकते। उल्लसित

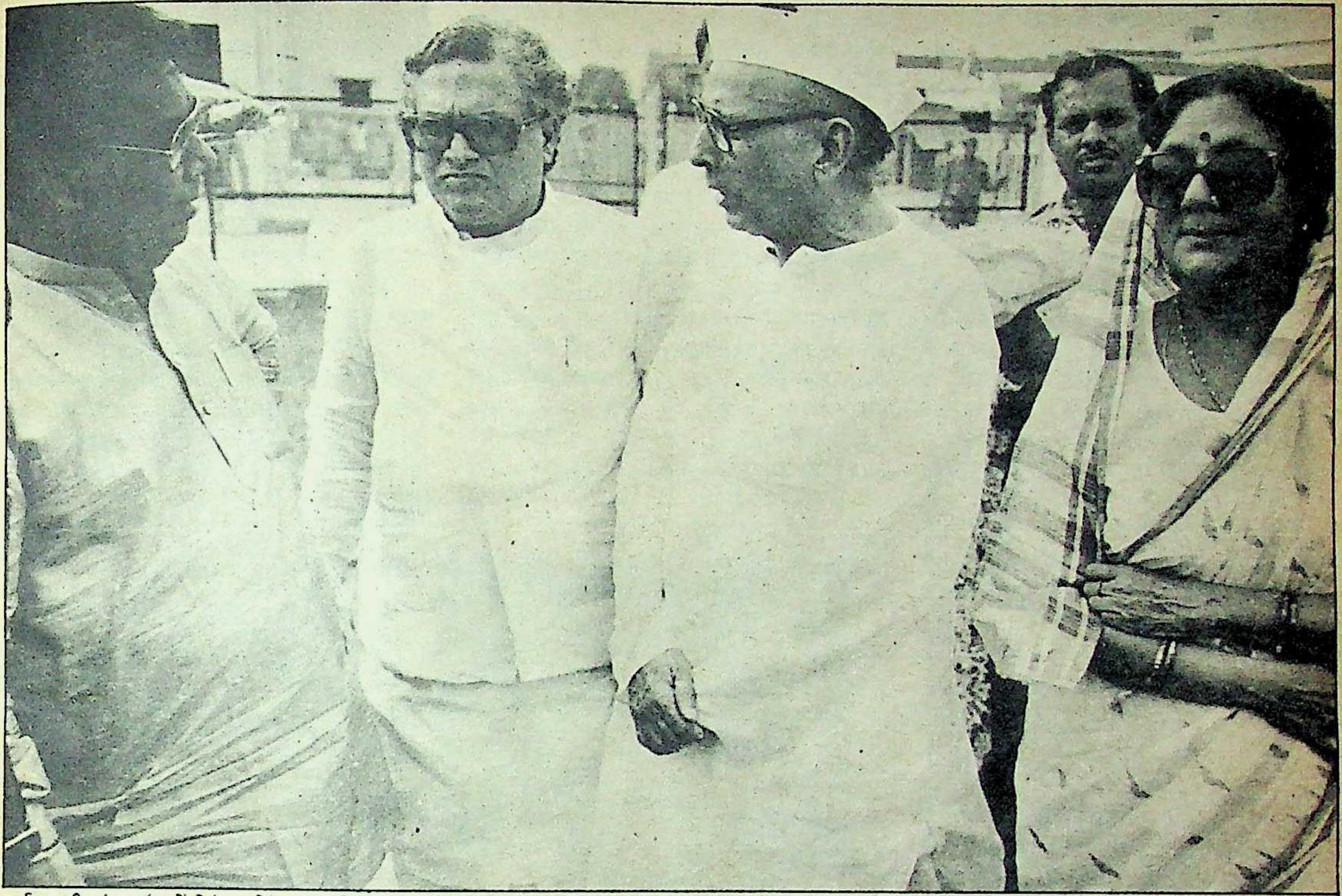

वर्चस्व की जंग: (बायें से) कांग्रेस महासचिव एआर मल्लू, जगन्नाथ मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिंह

जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के समापन के वाद कहा भी कि इस सभा की सफलता ने मुझसे ईर्ष्या व दुराव रखनेवालों को हमेशा के लिए चुप कर दिया। वाकई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भरपूर श्रेय लेने की कोशिश जगन्नाथ मिश्र ने की और इसमें कामयाब भी रहे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी से लेकर आमसभा के दौरान मंच पर भी जगन्नाथ छाये रहे।

मतभेद में इजाफा: १५ जून को पटना में कांग्रेस की विशाल आमसभा को संबोधित कर राजीव गांधी ने बिहार में चुनाव अभियान का श्रीगणेश तो अवश्य कर दिया, पर उस दिन से सत्येंद्र नारायण सिंह व जगन्नाथ मिश्र के मतभेद में भी काफी इजाफा हुआ। हालांकि शुरू से सत्येंद्र नारायण सिंह और जगन्नाथ मिश्र इस बात के लिए सचेत रहे हैं कि दोनों के बीच जितने दिन तक संभव हो, मुठभेड़ की स्थिति न आये। जब कभी राजनीतिक हलकों में दोनों के विवाद की कथा गर्म हुई या मतभेद के प्रसंग अखबारी सुर्खियों में आये, फौरन दोनों नेताओं ने खंडन किया। हाल में जगन्नाथ मिश्र ने तो यहां तक कह दिया कि सत्येंद्र नारायण सिंह और वे दो शरीर एक जान हैं। आपस में न लड़ने के दोनों नेताओं के अपने-अपने राजनीतिक तर्क हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद से हर दम यह सावधानी बरत रहे हैं कि उनकी किसी से सीधे-सीधे न ठने, ताकि यह बात साबित हो कि कांग्रेस में भविष्य के लिए भी वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं और इस आधार पर १९९० के विधानसभाई चुनाव के बाद उन्हें फिर मुख्यमंत्री का सिंहासन मिल जाये। सत्येंद्र नारायण सिंह इस प्रयास में जरूर रहते हैं कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं में महाभारत मचा रहे। इसके लिए वे कुछ दूर तक शह भी देते हैं। मसलन, पूर्व बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अनवर को आज तक उन्होंने प्रदेश की बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बरकरार रखा है। परंपरानुसार इस समिति का कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता है। भागवत झा आजाद ने भी अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उसी परिपाटी को ध्यान में रखकर तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अनवर को बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नामजद किया था। बाद में आजाद से मतभेद होने के कारण तारिक ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने उस समय तारिक का त्यागपत्र कबूल नहीं किया था, सो तारिक अध्यक्ष बने रहे। सत्येंद्र नारायण सिंह जब आजाद के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, तो तारिक ने फिर इस पद से अपना इस्तीफा उनके पास भेजा। यों जब तारिक ने शुरू में सत्येंद्र की काबीना में बतौर मंत्री शपथ लेने से इनकार कर दिया था, तो दोनों के बीच कुछ समय के लिए मतभेद की स्थिति बनी थी, पर जब तारिक ने सत्येंद्र से मिलकर स्पष्ट कर दिया कि उनकी लड़ाई जगन्नाथ मिश्र से है, तो सत्येंद्र को राहत मिली और सत्येंद्र ने तारिक से राजनीतिक रणनीति के तहत बीस सूत्री समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहने को कहा। लिहाजा, तारिक आज भी काबीना मंत्री स्तर की सुविधाएं भोग रहे हैं।

मुकाबला जगन्नाथ से: तारिक अनवर

तारिक के प्रति सत्येंद्र नारायण सिंह के इस सद्भाव से जगन्नाथ मिश्र का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। पिछले कुछ महीनों से तारिक ने जगन्नाथ के विरुद्ध जेहाद छेड़ रखा है। जगन्नाथ को बीस सूत्री कार्यान्वियन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने के लिए संबंधित विभाग के जगन्नाथ के एक चहेते अधिकारी ने मुख्यमंत्री के पास दो-तीन बार फाइल भिजवायी। पर बिना किसी टिप्पणी के मुख्यमंत्री ने उसे वापस कर दिया। जगन्नाथ यह भांप रहे हैं कि सत्येंद्र उनके विरोधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर खुद सामने आने से कतरा रहे हैं। शायद इसलिए तिक्त होकर जगन्नाथ ने कहा भी कि तारिक अनवर बीस सूत्री समिति के अध्यक्ष पद पर अब तक कैसे बने हैं, यह तो स्वयं मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह ने वाकई जगन्नाथ मिश्र को अपमानित करवाने का कोई अवसर अब तक नही छोड़ा है। पिछले दिनों जब राजीव गांधी पूर्णिया आये थे, तो सभा में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी बोलने का अवसर दिया जाना तय हुआ। बस फौरन सत्येंद्र नारायण सिंह ने पूर्व मंत्री सरयू मिश्र के पुत्र शंभुनाथ मिश्र को बोलने की अनुमति दिलवा दी। सत्येंद्र जानते थे कि शंभुनाथ उनकी इच्छानुसार प्रधानमंत्री के समक्ष जगन्नाथ मिश्र की आलोचना करेगा। वैसे ही हुआ भी। जगन्नाथ उस दिन हतप्रभ रह गये थे।

दरअसल, सत्येंद्र नारायण सिंह प्रधानमंत्री के समक्ष यह साबित करना चाहते थे कि आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जगन्नाथ मिश्र कितने विवादास्पद हैं। हाल में वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन में भी सत्येंद्र ने जगन्नाथ को कड़े झटके दिये। हुआ यों कि सत्येंद्र मंत्रिमंडल के काबीना मंत्री लहटन चौधरी और जगन्नाथ मिश्र एक ही समय सहरसा पहुंचे। कोशी रेंज के डीआईजी नारायण मिश्र ने लहटन के बजाय जगन्नाथ की ज्यादा आवभगत की। नारायण मिश्र की गिनती जगन्नाथ मिश्र के अति निकटस्थ अधिकारियों में होती रही है। नारायण की उपेक्षा से क्षुब्ध लहटन चौधरी पटना आये और मुख्यमंत्री कों विवरण दिया कि कैसे नारायण जगन्नाथ पर न्यौछावर हुए जा रहे थे। बस मुख्यमंत्री ने उसी दिन नारायण का कोशी रेंज से तबादला कर दिया। मधुबनी जिला जो जगन्नाथ मिश्र का राजनीतिक किला है, वहां भी सत्येंद्र नारायण सिंह ने बगैर जगन्नाथ की राय के जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक की पदस्थापना कर दी। मधुबनी के नये आरक्षी अधीक्षक नीलमणि जो इसके पूर्व भागलपुर में थे, पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के विश्वासपात्र माने जाते हैं, वहीं मधुबनी के नये जिलाधिकारी एमपी शुक्ल के संबंध पूर्व मंत्री नागेंद्र झा से अंतरंग रहे हैं। आजाद और नागेंद्र झा से जगन्नाथ के अत्यंत कटु संबंध हैं। जाहिर है जगन्नाथ सत्येंद्र नारायण सिंह द्वारा मधुबनी में किये गये प्रशासनिक परिवर्तन से अप्रसन्न हैं। बहरहाल, जिस तरह परोक्ष शैली में सत्येंद्र जगन्नाथ पर हमला करने में नहीं चूक रहे हैं, उसी तरह जगन्नाथ भी सत्येंद्र पर परोक्ष रूप से प्रहार करने की ताक में रहते हैं।

जगन्नाथ की परेशानी: जगन्नाथ हर दम यह साबित करने में लगे रहते हैं कि सत्येंद्र अत्यंत दुर्बल हैं, इसलिए दया के पात्र हैं। पिछले महीनों में जगन्नाथ जब भी किसी जिले के दौरे पर गये, तो पोस्टर व पर्चों में उनके साथ सत्येंद्र के आगमन का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से रहता ही था। पर सत्येंद्र कभी जगन्नाथ के साथ नहीं गये। लिहाजा, जिले के कार्यकर्ता जब जिज्ञासा करते कि कार्यक्रम निर्धारित होने के बावजूद मुख्यमंत्री क्यों नहीं आये, तो जगन्नाथ-समर्थक मायूस होकर सबको बताते कि मुख्यमंत्री बीमार होने की वजह से नहीं आये। जबकि सचाई यह थी कि सत्येंद्र का नाम बगैर उनकी जानकारी के पोस्टर-पर्चों में डाल दिया जाता। जब इन प्रसंगों की जानकारी सत्येंद्र को मिली, तो उन्होंने आपत्ति की और कहा कि बगैर उनकी अनुमति के जगन्नाथ अपने कार्यक्रमों में उनके आगमन संबंधी खबर छाप कर भ्रांति पैदा न करें। इसलिए इधर जगन्नाथ मिश्र फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। वे सत्येंद्र को क्रोध से नहीं, बल्कि उनके प्रति दया दिखाकर आहत करना चाहते हैं। १९९० की बाजी वे चूकना नहीं चाहते। इसलिए वे सत्येंद्र से अपनी अदावत को टाल रहे हैं। जगन्नाथ आलाकमान की अदालत में इस बार इस आरोप के साथ कठघरे में खड़े होने को तैयार नहीं कि चुनाव वर्ष में सत्येंद्र से झगड़कर जगन्नाथ ने पार्टी का अहित कर दिया। जगन्नाथ का एक सूत्री अभियान है कि सत्येंद्र शारीरिक रूप से रुग्ण हैं, इसलिए किसी तरह चुनाव तक समय काट लें, बाद में शासन की बागडोर थामने के लिए तो वे हैं ही। जगन्नाथ की यही महत्वाकांक्षा सत्येंद्र को भी विचलित करती रहती है।

साक्षात्कार: तारिक अनवर

'मुझे संतोष है कि जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस में हैं'

कटिहार के सांसद और बिहार इंका के पूर्व अध्यक्ष तारिक अनवर अपने घायल गुस्से में डा० जगन्नाथ मिश्र पर निरंतर प्रहार तेज ही करते जा रहे हैं। क्या जगन्नाथ को पस्त करने में तारिक कामयाब हो पायेंगे? आखिर उनकी जगन्नाथ विरोधी मुहिम का सबब क्या है? 'माया' से तारिक की बातचीत के मुख्य अंश:

माया: *जगन्नाथ मिश्र की भांति अब आपने भी बिहार में जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है। इसके पीछे सिर्फ जगन्नाथ पर वार करने का उद्देश्य है या कुछ और?*

तारिक: जगन्नाथ मिश्र तो मेरे उत्तराधिकारी हैं। भला कोई अपने उत्तराधिकारी से भी लड़ता है? हां, अपने उत्तराधिकारी को सदैव कर्त्तव्यनिष्ठ और मर्यादित बनाये रखने के लिए सचेत करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मुझे लगता है कि पार्टी के प्रति वे पूरी तरह निष्ठावान नहीं हो पा रहे हैं। यह खतरनाक बात है। मैं इसी संभावित खतरे को टालने की भरसक कोशिश कर रहा हूं। मेरी समझ से जगन्नाथ मिश्र अभी भी भयाक्रांत हैं कि कभी भी वे फिर से हाशिये पर फेंक दिये जा सकते हैं। इसलिए उनके भीतर का बागी अभी तक रह-रहकर चौंकता रहता है। जहां तक मेरे जनसंपर्क अभियान का सवाल है, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जगन्नाथ मिश्र के जनजागरण जैसा नहीं है। उनका जनजागरण नहीं, बल्कि पद-जागरण था। पद मिल गया, तो जागरण भी समाप्त हो गया। मेरी नीयत ऐसी नहीं है। मैं सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की आम जनता के बीच काम करने का अरमान रखता हूं। राजीव गांधी ने सभी कांग्रेसजनों को निर्देश दिया था कि प्रत्येक कांग्रेसी सीधे आमलोगों के सुख-दुख में सहभागी बने। मेरा जनसंपर्क अभियान राजीव गांधी के आदेश के तहत ही है। अब तक करीब ग्यारह जिलों का मैं दौरा कर चुका हूं और तीस से ऊपर जनसभाएं कर चुका हूं। बिहार के लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं इतना यकीन जरूर दिलाना चाहूंगा कि जगन्नाथ मिश्र की तरह मैं बिहार के लोगों के प्यार का कहीं सौदा नहीं करूंगा।

माया: *जगन्नाथ मिश्र के 'बिहार जन विकास मंच' के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसे भंग*

शुरू के कुछ महीनों में सत्येंद्र ने जगन्नाथ को झटका देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से अच्छा संबंध बनाये रखा था। पर जब सत्येंद्र को यह लगा कि आजाद भी १९९० में सिंहासन के एक दावेदार हो सकते हैं, तो सत्येंद्र आजाद से भी कन्नी काट गये। आजाद ने बिहार में अपना पदयात्रा-कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लखीसराय में आजाद की पहली पदयात्रा में जबर्दस्त भीड़ थी। आजाद की पदयात्रा किसी के प्रति विरोध से प्रेरित नहीं है, पर तारिक अनवर ने जिले-जिले में सिर्फ जगन्नाथ की जड़ कुरेदने के लिए जनसभाओं का दौर चला रखा है। धनबाद से जब जगन्नाथ मिश्र सभा करके लौटे, तो थोड़े ही दिनों बाद तारिक भी धनबाद में आमसभा कर आये और आकर एक बयान दागा कि जगन्नाथ की धनबाद-यात्रा सिर्फ माफिया का मनोबल बढ़ाने के लिए ही थी। धनबाद में केंद्रीय मंत्री बिंदेश्वरी दुबे के समर्थक विधायक ओम प्रकाश लाल तारिक की सभा को सफल बनाने के लिए प्राणपण से जुटे थे। दरअसल, दुबे ने अपने समर्थकों को निर्देश दे रखा है कि वे सब तारिक के जगन्नाथ विरोधी अभियान को सहयोग दें। यों सिर्फ सत्येंद्र नारायण सिंह और बिंदेश्वरी दुबे ही नहीं, जगन्नाथ से नाराज तमाम नेता नेपथ्य से तारिक की मदद कर रहे हैं कि तारिक जगन्नाथ पर धावा बोलते रहें। ५ जून को तारिक दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले और अपने जनसंपर्क अभियान के बारे में उन्हें जानकारी दी। तारिक 'माया' से कहते हैं, "प्रधानमंत्री ने मुझे कभी भी जगन्नाथ के विरुद्ध जंग बंद करने को नहीं कहा है। सो मैं आखिरी दम तक जगन्नाथ को एक्सपोज करता रहूंगा।"

विकास मंच बनाम कौमी तंजीम : जगन्नाथ मिश्र के 'बिहार जन विकास मंच' और तारिक अनवर के संगठन 'कौमी तंजीम' के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल, जगन्नाथ के एक समर्थक ने 'कौमी तंजीम' को जब सांप्रदायिक संगठन करार दिया, तो तारिक खेमे को उबलने का मौका मिल गया। तारिक 'कौमी तंजीम' के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तंजीम की बिहार शाखा के अध्यक्ष हैं तारिक समर्थक विधायक गुलाम हुसैन। १४ जून को गुलाम ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि 'कौमी तंजीम' संगठन सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से ही बना है और जगन्नाथ समर्थक तंजीम पर सांप्रदायिक होने का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ मिश्र को सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए।

जगन्नाथ के 'बिहार जन विकास मंच' के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा है। जगन्नाथ के आलोचकों ने लगातार मंच को भंग करने की मांग जारी रखी थी। लेकिन जगन्नाथ मंच को भंग करने के लिए कभी राजी नहीं हुए। जगन्नाथ ने तर्क भी ढूंढ़ लिया कि जब सत्येंद्र नारायण सिंह किसान मजदूर समन्वय समिति और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रह सकते हैं और तारिक अनवर कौमी तंजीम चला सकते हैं, तो वे क्यों नहीं जन विकास मंच के अध्यक्ष रह सकते ? जगन्नाथ का कहना था कि मंच के साठ हजार सदस्यों में से पचास हजार कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। जगन्नाथ-विरोधियों ने तर्क दिया कि मंच को जिंदा रख जगन्नाथ सदैव आलाकमान को बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने की धमकी दिये रखना चाहते हैं। दरअसल, जगन्नाथ जानते हैं कि जन विकास मंच के कारण ही वे प्रदेश कांग्रेस का मंच पा सके। यों मई के अंतिम सप्ताह में ही पटना के राजनीतिक गलियारों में खबर गर्म थी कि आलाकमान ने जगन्नाथ को अविलंब मंच का अध्यक्ष पद छोड़ने की हिदायत दी है। पर २ जून को जगन्नाथ ने पटना में बयान जारी कर कहा कि ऐसा कोई निर्देश उन्हें आलाकमान से नहीं मिला है। ७ जून को कांग्रेस महासचिव एआर मल्लू ने दिल्ली से बयान जारी किया कि जगन्नाथ मंच का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। पर इसके बावजूद जगन्नाथ मंच से मुक्त नहीं हुए। १२ जून को अचानक समाचार एजेंसियों ने खबर जारी की कि जगन्नाथ ने मंच का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। पर १३ जून को ही जगन्नाथ के हवाले से फिर खबर छपी कि मंच का अध्यक्ष पद उन्होंने नहीं छोड़ा है।

क्या जगन्नाथ मिश्र सचमुच राजीव गांधी के पास अपनी साख जमाने में कामयाब हो रहे हैं या दोनों के बीच शक का वही पुराना संबंध रेंग रहा है, इस सवाल पर राजनीतिक गलियारों में बहस गर्म है। यों १५ जून को पटना में प्रधानमंत्री की आमसभा के बाद से जगन्नाथ-खेमा काफी उत्साहित है। जगन्नाथ समर्थकों को लग रहा है कि इस सफल आयोजन से दोनों के बीच का रहा-सहा कुहासा भी छंट गया है। पर क्या सचमुच कुहासा छंट गया है ?

—विकास कुमार झा

छाया : दीपक कुमार

कर देना चाहिए ?

तारिक : बेशक इसे भंग किया जाना चाहिए। इस मंच की पैदाइश हमारे नेता राजीव गांधी का बिहार में विरोध करने के लिए हुई थी। इसका सबूत है कि गत वर्ष ३ दिसंबर को जब जगन्नाथ मिश्र ने मंच की पहली बैठक की थी, तो उसमें सभी विरोधी दलों के नेता आमंत्रित किये गये थे। उस मंच से राजीव गांधी और नेहरू परिवार को गालियां दी गयीं। मंच की पहली बैठक की अध्यक्षता पूर्व कुलपति डा० शकीलउर्रहमान ने की थी जो अभी जनता दल में हैं। इस मंच का अस्तित्व प्रतिपल कांग्रेस और राजीव गांधी का अपमान है।

माया : *पर जगन्नाथ खेमे का आरोप है कि आप भी कांग्रेस से अलग 'कौमी तंजीम' नामक संगठन चला रहे हैं ?*

तारिक : जन विकास मंच की तरह कौमी तंजीम को कभी भी मैंने विपक्ष का प्लेटफार्म नहीं बनाया। कौमी तंजीम तो कांग्रेस की राष्ट्रीय भावधारा का एक अंग है, जिसका गठन हमने अपने नेता राजीव गांधी की जानकारी में किया। देश के अल्पसंख्यकों से जुड़े राजीव गांधी के जो कार्यक्रम हैं, उन्हें आमलोगों तक पहुंचाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ओर मैं कांग्रेस में हूं और कौमी तंजीम के जरिये कांग्रेस को गाली दिलवा रहा हूं। जन विकास मंच के जरिये जगन्नाथ मिश्र बस यही काम करते रहे हैं।

माया : *जगन्नाथ मिश्र का यह दावा रहा है कि बिहार में वे मुस्लिमों के भी नेता हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं ?*

तारिक : दरअसल, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के वास्ते जो बातें कही गयी थीं, जगन्नाथ मिश्र ने उसे अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बताकर मुस्लिमों के बीच वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। पर बिहार के अल्पसंख्यक सचाई से वाकिफ हैं।

माया : *प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के पहले तक तो आपके संबंध जगन्नाथ मिश्र से बहुत अंतरंग थे ?*

तारिक : राजनीतिक तौर पर तो कभी हमारे संबंध नहीं रहे। हां, बाद के कुछ दिनों में मैंने यह कोशिश अवश्य की कि किसी तरह उन्हें कांग्रेस से निकलने से रोका जाये। वे कांग्रेस छोड़ने का पूरी तरह मन बना चुके थे। चुनाव वर्ष में क्योंकि छोटे-से-छोटे कार्यकर्ता की अहमियत होती है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि जगन्नाथ मिश्र भी कांग्रेस में रह जायें, तो बेहतर होगा। मुझे संतोष है कि आज वे कांग्रेस में हैं। मेरा प्रयास सफल रहा।

माया : *आपके बाद ही जगन्नाथ मिश्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। क्या आप मानते हैं कि आपके बाद संगठन का काम और कायदे से चल रहा है ?*

तारिक : कांग्रेस का जो पारंपरिक कार्यकर्त्ता है वह तो बगैर किसी लोभ-लालच के सदैव सक्रिय रहता आया है। पर संगठन के कामकाज में जगन्नाथ मिश्र की विवादास्पद छवि बाधक जरूर हो रही है। लोग उनके मुख्यमंत्रित्वकाल का कड़ुवा अनुभव भूल नहीं पाये हैं। हां, सत्येंद्र नारायण सिंह ने बहुत जल्दी कांग्रेस जनों को अपने विश्वास में लिया है।

माया : *बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष पद पर आपके बने रहने को लेकर राजनीतिक हलके में काफी चर्चा है। परंपरानुसार तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही होते रहे हैं, इसलिए अब तो इस कुरसी के हकदार जगन्नाथ मिश्र हैं ?*

तारिक : सत्येंद्र नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, तो उसके ठीक दो दिन बाद ही मैंने बीस सूत्री समिति के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने पद पर बना रहूं। सो मैं हूं। अगर जगन्नाथ मिश्र इस पद के लिए उत्सुक हैं, तो वही बन जायें।

—विकु झा

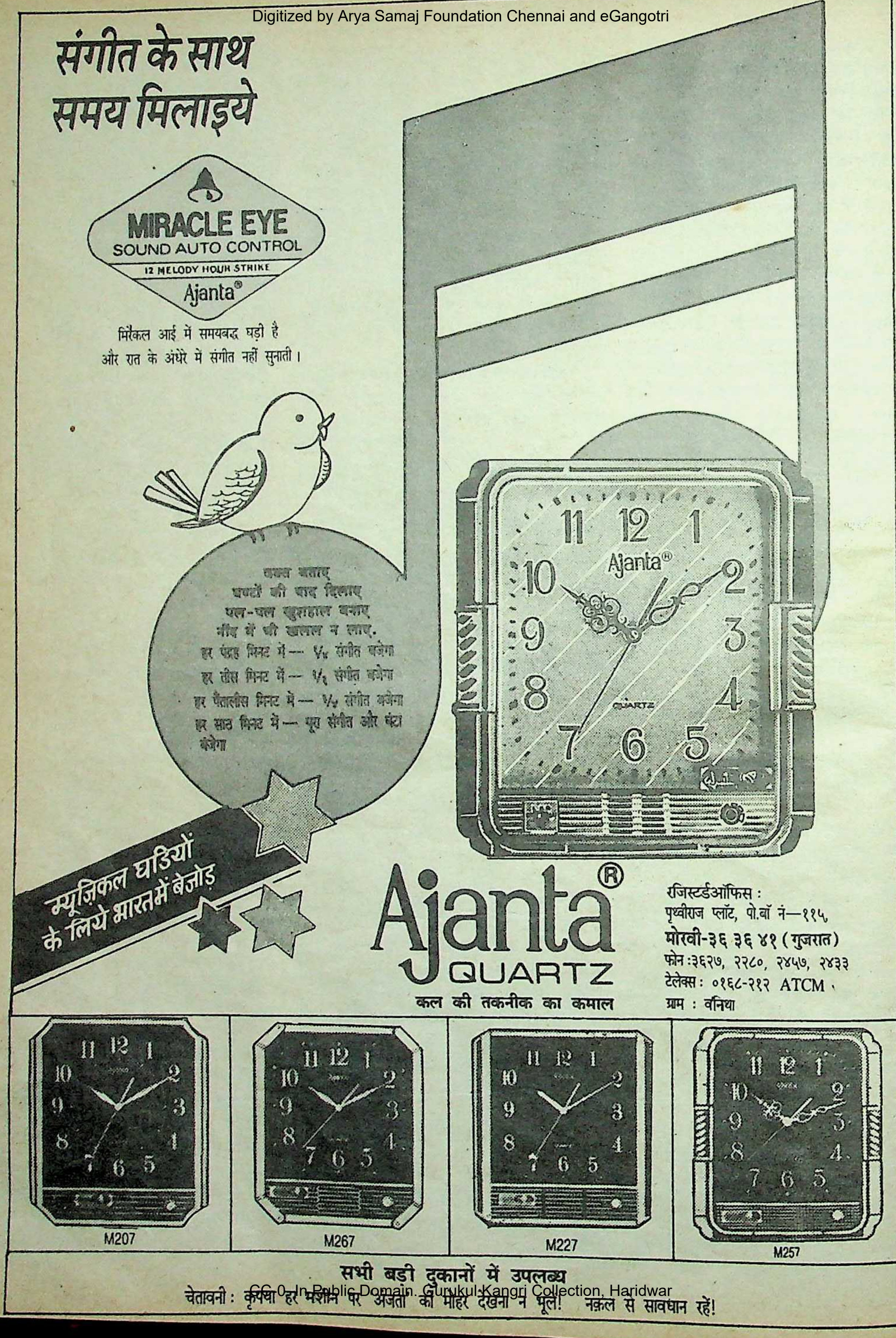
संगीत के साथ
समय मिलाइये
MIRACLE EYE
SOUND AUTO CONTROL
12 MELODY HOUR STRIKE
Ajanta®
Ajanta®
QUARTZ
म्यूज़िकल घड़ियों
के लिये भारतमें बेजोड़
Ajanta®
QUARTZ
M207
M267
M227
M257

मिरैकल आई में समयबद्ध घड़ी है
और रात के अंधेरे में संगीत नहीं सुनाती।

वक्त बताए
घण्टों की याद दिलाए
पल-पल खुशहाल बनाए
नींद में भी खलल न लाए.
हर पंद्रह मिनट में— 1/4 संगीत बजेगा
हर तीस मिनट में— 1/2 संगीत बजेगा
हर पैंतालीस मिनट में— 3/4 संगीत बजेगा
हर साठ मिनट में— पूरा संगीत और घंटा बजेगा

कल की तकनीक का कमाल

रजिस्टर्डऑफिस :
पृथ्वीराज प्लॉट, पो.बॉ नं—११५,
मोरवी-३६ ३६ ४१ (गुजरात)
फोन :३६२७, २२८०, २४५७, २४३३
टेलेक्स : ०१६८-२१२ ATCM .
ग्राम : वनिथा

सभी बड़ी दुकानों में उपलब्ध

चेतावनी : कृपया हर मशीन पर अजंता की मोहर देखना न भूलें! नक़ल से सावधान रहें!

न्यायपालिका को श्रमिक नेता की चुनौती

श्रमिक नेता नारायण प्रसाद शर्मा, सरकारी सेवा से मुक्त होने और उच्चन्यायालय के विपरीत फैसले के बावजूद किस बलबूते पर पौने चार लाख सदस्योंवाले मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर जमे हुए हैं और उच्चन्यायालय के फैसले का मखौल उड़ा रहे हैं?

शक्तिप्रदर्शन : कर्मचारी आंदोलन का नेतृत्व करते नारायण प्रसाद शर्मा (इनसेट)

मप्र राज्य तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के विवादास्पद अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा अपने अस्तित्व के लिए इन दिनों 'खंदक की लड़ाई' लड़ रहे हैं। कर्मचारी संघ पर उनका बरसों का एकाधिकार टूट चुका है और अपनी कुरसी और साख बचाने के फेर और अंतिम दम तक लड़ने की आत्मघाती झोंक में उन्होंने न्यायपालिका से भी बैर मोल ले लिया है। प्रशासन की सतर्कता व तगड़े पुलिस बंदोबस्त के कारण नारायण प्रसाद शर्मा अपने इरादे में विफल रहे, अन्यथा वे १२ जून को जबलपुर हाईकोर्ट और न्यायमूर्ति बीएम लाल के आवास के समक्ष प्रदर्शन करने और न्यायमूर्ति का पुतला जलाने की घोषणा कर चुके थे। अपने करीब साढ़े तीन सौ साथियों की गिरफ्तारी के बाद कर्मचारी नेता ने घोषणा की कि भावी कार्रवाई के निर्धारण के लिए भोपाल में १२ जुलाई को संघ की कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गयी है। न्यायपालिका से टकराव को सन्नद्ध प्रतीत होते शर्मा क्या तय करते हैं, इसका पता तो बैठक के बाद चलेगा, किंतु जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके बयानों और कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए न केवल उनके नाम अदालत की अवमानना की नोटिस जारी की है, वरन उन्हें २८ जून को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि : अतीत की घटनाओं पर दृष्टिपात करें, तो साफ है कि शर्मा 'मिट्टी के माधो' नही हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के शक्तिशाली और विशालतम संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर वे पिछले करीब बाईस वर्षों से काबिज रहे हैं। यह उनकी संगठन क्षमता, कूट-कौशल और दूसरी खूबियों का कमाल है कि बरसों से संघ में उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं खड़का है। सरकार की नाक में दम करने में उन्हें महारत हासिल है और अपनी इस खूबी का सुबूत वे कई बार दे चुके हैं। १२ जून को भी जब जबलपुर में उनके तमाम साथी गिरफ्तार हुए, तब समूचे खेल के सूत्रधार होने के बावजूद प्रशासन ने उन पर हाथ नहीं डाला, लिहाजा वे गिरफ्तारी से बच गये।

शर्मा की उपलब्धि और सफलता इस नाते आश्चर्यजनक और उल्लेखनीय है कि वे निष्कलंक और निर्विवाद नेता नहीं हैं। उन पर दादागीरी से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हैं। विभागीय जांच में भी वे दोषी पाये गये। और-तो-और, एक बार वे सेवा से अलग भी किये जा चुके हैं। इसके बाद भी हकीकत यह है कि उनका बाल बांका नहीं हुआ और उनकी सल्तनत बरकरार रही। इसका एक कारण उनकी पूर्वोल्लिखित खूबियों के अलावा यह भी है कि उन्होंने ऐसे शक्तिशाली सत्ताधीशों से जीवंत और मजबूत संबंध बनाये, जिनके हाथ लंबे थे।

कर्मचारी संघ नारायण प्रसाद शर्मा की 'सल्तनत' इस मायने में है कि लगभग पौने चार लाख शासकीय कर्मचारी इसके सदस्य हैं और कुछ समय पूर्व तक शर्मा के फैसले सर्वोपरि हुआ करते थे। शर्मा स्वास्थ्य विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक पद पर कार्यरत हैं। दक्षिण भोपाल से वे विधानसभा के लिए टिकट के दावेदार भी रहे हैं। पूर्व कर्मचारी नेता व विधायक (स्व) मोहनलाल अस्थाना के खिलाफ चुनावी याचिका में उनकी गवाही काफी महत्वपूर्ण रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनाव में वे एक बार फिर टिकट के लिए इंका आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक दें।

आरोपों की जांच : पिछले दशक के अंतिम बरसों में शर्मा पर ८०,५७० रुपयों के गबन का आरोप लगा था। मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ की धारा ३१ (१) के अधीन जांच अधिकारी एएम सक्सेना ने १७ जुलाई, ७९ को प्रतिवेदन दिया था कि शर्मा कर्मचारी भवन बनाने हेतु भूखंड के आवंटन और एक्शन फंड की रकम के दुरुपयोग के दोषी हैं। सन् '७९ में उनके क्षय चिकित्सालय और टीटी नगर अस्पताल के कार्यकाल की जांच हुई थी। इस विभागीय जांच में यह निष्कर्ष निकला था कि शर्मा ने अपने कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचायी। सरकारी नोटिसों का उत्तर न देने और अनियमितताओं का दोषी पाये जाने पर स्वास्थ्य सेवाओं के तत्कालीन संचालक प्रकाश नारायण ने शर्मा को सेवा से हटा दिया था। अनियमितताओं के दोषी पाये गये इस नेता की बहाली की कथा भी कम विचित्र नहीं है। भाजपा विधायक हिम्मत कोठारी ने २७ मार्च '८१ को विधानसभा में इस बारे में प्रश्न उठाया था। तत्कालीन मंत्री झुमुकलाल भेंडिया ने सदन में स्वीकार किया कि कर्तव्यपालन में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और अस्पताल में वेतनों की

अफरा-तफरी के आरोपों के विभागीय जांच में प्रमाणित होने पर शर्मा को सेवा से पृथक किया गया था। आगे बहाली का कारण बताते हुए भेंडिया ने कहा कि इनकी अपील पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर इन्हें पुनः बहाल किया गया है।

स्पष्ट है कि शर्मा की मानवीय आधार पर बहाली ने उन्हें उनकी सल्तनत लौटा दी। जनता सरकार ने नौकरी से उनकी 'छुट्टी' की थी, किंतु कांग्रेस-इ के पुनः सत्तारोहण के बाद उन्हें नौकरी भी मिली और खोयी हुई सल्तनत भी। बताते हैं कि इस 'महान उपकार और कृपा' को शर्मा आज तक नहीं भूले हैं। उनके फैसलों और उनकी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में वह घटना संभवतः आज भी अहम भूमिका निभा रही है।

आघात : कर्मचारी संघ पर उनका बरसों का एकाधिकार तब टूटा, जब २ मार्च '८६ को पंचम व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती रीता नटराजन ने फैसला सुनाया कि शर्मा का कार्यकाल २७ दिसंबर '८८ को समाप्त हो चुका है, अतः उन्हें पद पर कार्य करने की वैधानिक पात्रता नहीं है। अदालत ने वादी रामबिहारी शर्मा के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी कर शर्मा के बतौर प्रांताध्यक्ष कार्य करने और १६-२० फरवरी की बैठक में पारित प्रस्तावों के अमल पर रोक लगा दी।

इस निषेधाज्ञा और तत्संबधित फैसले के बाद न्यायपालिका और नारायण प्रसाद के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ, वह अभी भी जारी है। शर्मा ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करते हुए २२ से २५ मार्च के दरम्यान बैठक बुलायी। बैठक में वही हुआ, जो वे चाहते थे, वे कर्मचारी संघ के शीर्षस्थ पदाधिकारी बन गये। लेकिन २३ मई को न्यायमूर्ति बीएम लाल ने एक याचिका पर फैसला सुनाया कि यह चुनाव निर्वाचन नियमों के विपरीत है। उन्होंने निर्वाचन कार्रवाई पर निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिया कि कर्मचारी नेता सुरेंद्रकुमार त्रिपाठी के निरीक्षण में चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित कर चुनाव कराये जा सकते हैं।

विरोधी गुट : ये सुरेंद्रकुमार त्रिपाठी कौन हैं, जिनका उल्लेख जस्टिस लाल ने अपने फैसले में किया है? वस्तुतः त्रिपाठी कर्मचारियों के एक धड़े के नेता हैं और शर्मा के प्रतिद्वंद्वी नेताओं में गिने जाते हैं। शर्मा के अध्यक्षकाल में त्रिपाठी संघ के महामंत्री थे। फिलहाल वे मप्र राज्य तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष और मप्र शासन से मान्यता प्राप्त हैं। मप्र शासन के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण के उपसचिव केएन श्रीवास्तव ने २४ अप्रैल '८६ को एक आदेश जारी किया कि शासन ने शर्मा के कार्यकाल के समाप्त हो जाने को ध्यान में रख कर संघ के प्रांताध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी को मान्यता देने का निर्णय लिया है। शासन के इस निर्णय की लिखित जानकारी समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्षों और सभी जिलाध्यक्षों को भेजी गयी।

शर्मा इन दिनों 'दोहरी लड़ाई' लड़ रहे हैं। एक ओर उनकी लड़ाई सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी से है और दूसरी ओर न्यायपालिका से। न्यायपालिका को वे सम्मान देने के मूड में नजर नहीं आते। जस्टिस लाल के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया अपनी तरह की पहली घटना है। उन्होंने न केवल फैसले को अमान्य किया, वरन कहा कि यह फैसला दुराग्रह व राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह कहकर लोनिवि मंत्री कुमारी विमला वर्मा को भी विवाद में खींच लिया कि उन्होंने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान फैसले को प्रभावित किया है।

शर्मा उपरोक्त आशय के बयान देने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जस्टिस लाल का पुतला जलाने, उनके बंगले और उच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन करने की भी घोषणा कर डाली। भोपाल में व अन्यत्र दीवारों पर ऐसे पोस्टर चस्पा किये गये, जिनमें न्यायपालिका व उसके फैसले का मखोल उडाया गया था। इन पोस्टरों में मोतीलाल वोरा, रामेश्वर नीखरा, केएन प्रधान, विमला वर्मा का भी उल्लेख है। शर्मा के इस आचरण को चिंतनीय करार देते हुए उनके प्रतिद्वंद्वी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी कहते हैं, "शर्मा सदैव फर्जी चुनाव कराकर दादागीरी के बल पर यूनियन पर काबिज रहे।" वे शर्मा के नेतृत्व में २२ मई को फटाफट संपन्न निर्वाचन को संदिग्ध निरूपित करते हैं और कहते हैं कि शर्मा का यह कथन हास्यास्पद है कि चुनाव में १२८० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कारण यह कि निर्वाचन नियमावली के अनुसार प्रत्येक पांच सौ सदस्यों पर एक प्रतिनिधि मतदान करता है। १२८० प्रतिनिधियों के मतदान की बात को सही मानें, तो कर्मचारियों की संख्या ६ लाख ४० हजार ठहरती है, जबकि प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या इससे कहीं कम है।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संघ के नेता सत्य नारायण सिंह शर्मा पर एक और आरोप लगाते हैं। सिंह का कहना है कि शर्मा ने करीब २८ लाख रुपयों की राशि हड़पी है। मिसाल के तौर वे बताते हैं कि संघ के संविधान में आजीवन सदस्यता का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु शर्मा ने १३ हजार आजीवन सदस्य बनाये और प्रत्येक से ७५ रुपए लेकर पौने दस लाख रुपए एकत्र कर लिये। त्रिपाठी व सिंह का साझा आरोप है कि शर्मा के पास कम-से-कम पंद्रह लाख रुपए की अचल संपत्ति है जो काली कमाई से हासिल हुई है, अन्यथा शर्मा स्वास्थ्य विभाग में 'इस्टीवर्ड' (अब डायटीशियन) जैसे सीमित आय के पद पर कार्यरत हैं। एक और आरोप यह है कि वे संघ की रकम से क्रय अंबेस्डर कार क्रमांक एमओसी ६५४५, तीन स्कूटरों (एमआईबी ५३४२, सीआईसी ६८४१, सीपीएम ७०६८), एक मोपेड व दो अन्य स्कूटरों का निजी हित में इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, के लिखित निर्देशों के बाद भी अपना चार्ज विधिवत निर्वाचित व मान्यताप्राप्त अध्यक्ष को नहीं दिया है। कार एवं स्कूटर दिलाने की रपट भोपाल में थाना तात्याटोपे नगर में भी दर्ज है, किंतु पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई करने में विफल रही है।

शर्मा के प्रतिद्वंद्वी : सत्यनारायण सिंह

घातक मोड़ : हजारों समर्थकों की दृष्टि में शर्मा 'जांबाज' नेता हो सकते हैं, किंतु विधि-विधान मर्यादाओं और परंपराओं में आस्था रखनेवालों के लिए उनका ताजा आचरण उलझन पैदा करनेवाला है। हाईकोर्ट को घेरने और न्यायमूर्ति का पुतला जलाने की कार्रवाई से किसी अभियान की शुरुआत लोकतांत्रिक समाज में कतई 'शुभ लक्षण' नहीं है। प्रश्न इन दो घटनाओं के तात्कालिक महत्व का नहीं बल्कि उन भयावह खतरों का है जो इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। शर्मा के फैसलों के साथ यह संदर्भ भी नत्थी है कि उनकी पीठ पर एक शक्तिशाली राजनीतिक लाबी का हाथ है। न्यायपालिका को चुनौती और उसके खिलाफ सड़क पर ताल ठोंकने के अभियान की अंतिम परिणिति कहां होगी, कहा नहीं जा सकता। इस बीच हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमके सेठ ने न्यायालय के चुनाव स्थगन, के निर्णय को स्वीकार करने से इंकार करने पर शर्मा के नाम न्यायालय की अवमानना की नोटिस जारी की है।। शर्मा अबतक रजिस्ट्रार व जांच अधिकारियों की नोटिसों को ठेंगा दिखाते आ हैं। देखना है कि शर्मा नयी नोटिस के साथ क्या सलूक करते हैं। जहां न्यायालय अभिभाषक संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर जबलपुर में प्रदर्शन के फैसले की निंदा की है, वहीं मप्र विकास परिषद के संयोजक आदर्शमुनि त्रिवेदी, अधिवक्ता के वक्तव्य से यह संकेत भी मिला है कि बार कौंसिल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकती है कि आइंदा कोई भी वकील नाप्र शर्मा का केस नहीं लड़ेगा। फिलहाल समूचा प्रसंग नाजुक घातक मोड़ पर है। इस घटनाक्रम का परिणाम इस नाते महत्वपूर्ण होगा कि इससे लोकतंत्र में न्यायपालिका के भविष्य का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

—सुधीर सक्सेना

मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान के दौरान

आपकी सरकार : आपके द्वार

साधारण जन की छोटी-छोटी समस्याएं मौके पर सुलझ जायें, उन्हें अनाज, मिट्टी का तेल, जलाऊ लकड़ी, खाद-बीज जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें वाजिब कीमत पर मिल जायें, बैंक ऋण लेने और जमीनों के खसरा-खतौनी में नामांतरण कराने में उन्हें परेशानी न हो—इसके लिए मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने 'आपकी सरकार, आपके द्वार' नाम से ९ मई को एक अनूठे कार्यक्रम की घोषणा की और १५ मई से उस पर अमल भी शुरू कर दिया। इस योजना के अंतर्गत अब गांववालों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि खुद सरकार उनके विकास खंड मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक शिविर लगायेगी और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करेगी। कलेक्टर इन शिविरों को आयोजित करेंगे, संभागीय कमिश्नर इनमें भाग लेंगे और विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री इनकी निगरानी करेंगे। इन शिविरों में कामकाज सुबह से शुरू होकर आठ-दस घंटों तक तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी शिकायतों का निपटारा नहीं हो जाता।

ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने क्षेत्र के सभी परिवारों से घर-घर जाकर संपर्क करके उनकी समस्याओं की सूची बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने खास तौर से पत्र लिखे हैं। इस सूची को वे शिविर लगने से पहले विकास खण्ड अधिकारी को भेजेंगे। इन शिविरों में अपनी शिकायत लेकर आनेवाले लोगों के लिए, नाश्ते, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार की ओर से की जायेगी। कलेक्टर इन शिविरों में किये गये काम की विस्तृत रिपोर्ट हर माह सरकार को भेजेंगे तथा जिन समस्याओं का निराकरण इन शिविरों में नहीं हो सकेगा, उन पर सरकार की ओर से तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश व्यापी अभियान: १५ मई को बस्तर जिले के बस्तर गांव में 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान का मुख्य मंत्री मोतीलाल वोरा ने श्रीगणेश किया। इस शिविर में प्राप्त ९५५ शिकायतों में से ९३ प्रतिशत का निराकरण हुआ। मुख्य रूप से २३० ऋण पुस्तिकाओं, १२९ नामांतरण और बंटवारे के पांच प्रकरणों का निपटारा किया गया। १३० रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें औषधि दी गयी। इसी प्रकार वनमंत्री डा० कन्हैयालाल शर्मा की उपस्थिति में घरसीवां में लगे शिविर में ४.१५ लाख रुपए के ऋण, १२० टन रासायनिक खाद, ११० क्विंटल धान बीज का वितरण हुआ तथा नौ लोगों को भू-कब्जे के प्रमाण पत्र दिये गये। गुना जिले के बमोरी विकास खण्ड के ग्राम फतेहगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवप्रताप सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया, जहां ५ हजार ग्रामवासी उपस्थित थे तथा समस्याओं के ३८२१ आवेदन पत्रों में से ३१९८ आवेदन पत्रों का मौके पर निपटारा किया गया। इसी प्रकार ग्वालियर जिले में पहला शिविर उटीला गांव में सहकारिता मंत्री श्री बालेंदु शुक्ल की उपस्थिति में लगा, जहां राजस्व विभाग के ८६ प्रकरण, सीमांकन के ७, नामांतरण के ७, ऋण पुस्तिका वितरण के ३७ तथा प्रमाणीकरण के ४२ मामले निपटाए गये। अनेक गांवों में एक-एक हैंडपंप लगाने की स्वीकृति भी दी गयी। इसी प्रकार अलीराजपुर (झाबुआ) में भी ऐसे शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है और प्रदेश के सभी ४५९ विकास खण्ड मुख्यालयों में ऐसे शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविर में आदिवासियों के आवेदन पत्र लिखने की व्यवस्था भी की जाती है।

सरकार को जनोन्मुखी बनाने और लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुलझाने की दिशा में किया गया यह प्रयास निश्चय ही प्रदेश की जनता में नया विश्वास और उत्साह जगायेगा।

विज्ञापन

आपकी सरकार आपके द्वार

देहाती इलाकों में लोगों की समस्याएं और तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने शुरू किया है एक नया कार्यक्रम

आपकी सरकार आपके द्वार

इस कार्यक्रम का मतलब यह है कि मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, पहले से तयशुदा दिनों में सभी ब्लाक मुख्यालयों का दौरा करेंगे और आपकी समस्या रूबरू सुनेंगे, इस दौरान जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उनके साथ रहेंगे। जिन समस्याओं का निपटारा तुरन्त हो सकेगा, उन्हें वहीं के वहीं निपटा दिया जायेगा। जिन मामलों में तुरन्त फैसला नहीं हो सकता उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्दी निपटाने की कार्रवाई शुरू की जायेगी।

गांव-गांव खुद आकर सुने सरकार
आपकी बात

यानी जो लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते उनकी बात सुनेगी सरकार खुद उनके घर आकर।

हकदार की तरफदार — मध्यप्रदेश सरकार

विज्ञापन

ऐसी हर खबर के

पीछे हैं

मेहनत और तालमेल की कहानी

Collection of tendu leaves in full swing
BHOPAL: The tendu leaf collection work is going on in full swing in 10 divisions of the State. Till May 10, 1989, 4 lakh 93 thousand and 872 standard bags of tendu leaf has been collected in these
तेंदूपत्ता संग्रहण
बस्तर जिले में अनेक कारणों से
तेंदूपत्ते के संग्रहण का काम शुरू
रायपुर में ८८ हजार
Tendu collection in full swing
रे तेंदूपत्ता संग्रहीत
May 12 (PTI): Collec
तेन्दूपत्ता का संग्रहण
भोपाल। प्रदेश के दस संभागों में
तेन्दूपत्ता संग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। १० मई तक प्रदेश में ४ लाख ९३ हजार
८७२ मानक बोरा तेन्दूपत्ता

लाखों लोगों के हकों की कहानी

10 लाख लोग

इस मौसम में करीब 10 लाख लोग तेंदूपत्ता तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग आदिवासी हैं। 42 हजार से ज्यादा गांवों में बसे ये लोग इस मौसम में करीब 60 लाख बोरे तेंदूपत्ता इकट्ठा कर रहे हैं

इन सब लोगों को 1947 सहकारी समितियों की सदस्यता दी गयी है।

28,000 भुगतान केंद्र

तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वालों को तुरन्त भुगतान के लिए 28,000 फड़ों का इंतजाम यानी इतने ही फड़मुंशियों के जरिये हर रोज आने वाले तेंदू पत्ते की कीमत चुकाई जाती है।

फड़ों तक पैसा पहुंचाने के लिए 2500 जीपों, 400 मोटर साइकिलों और 10,000 साइकिलों का इंतजाम किया गया है।

पैसे के लेखे जोखे के लिए सरकार के अलग-अलग विभागों के दस हजार कर्मचारी पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं।

74% ज्यादा भुगतान

सरकार के फैसले के मुताबिक सभी तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को अपनी उपज की कीमत 15 रुपये प्रति सौ गड्डी के हिसाब से दी जा रही है-पिछले बरस के 8.50 रुपये के मुकाबले 76% ज्यादा। ...और साथ में हर परिवार के लिए खाद्यान्न भी।

90,000 और लोगों को काम

इतने बड़े पैमाने के काम में 90 हजार और लोगों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। इनमें से 40 हजार लोग फड़मुंशी, चेकर और हेड चेकर के जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं।

बोरों में पत्ता भरने के काम में भी करीब 50 हजार कुशल मजदूरों को काम मिलेगा।

1,50,000 बैलगाड़ियों में ढुलाई

फड़ों से गोदामों तक माल पहुंचता है-डेढ़ लाख बैलगाड़ियों और 60 हजार ट्रक फेरों के जरिए कई मंजिले तय करते हुए।

50,000 कर्मचारी

विभिन्न विभागों से 50,000 अधिकारियों-कर्मचारियों की बड़ी टीम पूरे मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण के इंतजाम में जुटी हुई है।

इस टीम में 30 हजार अधिकारी-कर्मचारी वन विभाग के हैं जिनके तजुर्बे का फायदा इस बड़े काम में मिल रहा है।

इतने लोगों और उनकी इतनी मेहनत की कहानी ही है-तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के हकों की बहाली की कहानी।

हकदार की तरफदार
मध्यप्रदेश सरकार

विज्ञापन

छोटे किसानों के लिए

कर्ज मिलना जितना आसान अदायगी उससे भी ज्यादा आसान

अल्पावधि ऋण सभी छोटे किसानों को

अभी तक केवल आदिवासी और हरिजन लघु और सीमांत किसानों को रियायती दर पर मिलने वाले अल्पावधि ऋण अब सभी लघु और सीमांत किसानों को मिल सकेंगे।

ब्याज की दर में कमी

अल्पावधि ऋणों पर लघु और सीमांत हरिजन-आदिवासी किसानों के लिए ब्याज की दर दो प्रतिशत कर दी गयी है। दूसरे वर्गों के लघु और सीमांत किसानों को ये कर्ज ६ प्रतिशत की रियायती दर पर मिलेंगे। बैंकों को ब्याज में होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसानों को इससे 5 करोड़ रुपये की राहत इसी साल मिलेगी।

सूखा प्रभावित किसानों को रियायती दर पर कर्ज

अभी तक सूखा प्रभावित किसानों को दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण मध्यावधि ऋणों में बदल दिये जाते थे और उन पर सामान्य दर से ही ब्याज लगता था। अब ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर दो प्रतिशत कम कर दी गयी है। इसका फायदा बड़ी संख्या में सूखा पीड़ित किसानों को होगा। इस साल, सरकार के इस कदम से किसानों को कुल 5 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

अब दण्ड ब्याज भी खत्म

किसानों को और राहत देने के लिए सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज पर लगने वाला दंड ब्याज भी समाप्त कर दिया है। डिफॉल्ट होने पर भी बकायादार किसानों से सामान्य दर पर ही ब्याज लिया जायेगा। दंड ब्याज खत्म करने से बैंकों को नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, यानी करीब 6 करोड़ रुपये हर साल।

नेहरू शताब्दी वर्ष · किसानों के हक में
फैसलों का साल

फैसले किसानों के हक में

-मध्यप्रदेश सरकार

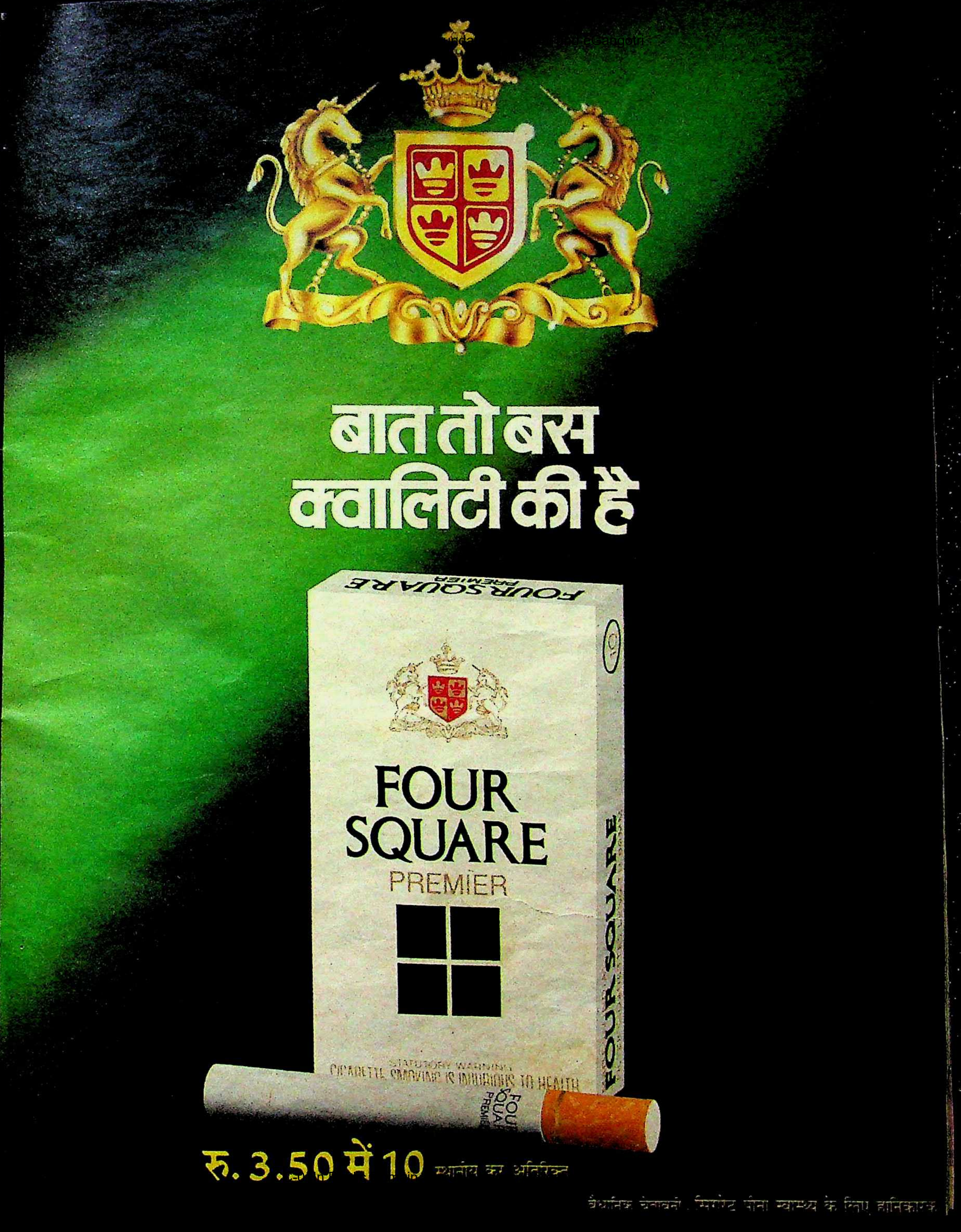

बात तो बस
क्वालिटी की है
FOUR SQUARE PREMIER
FOUR SQUARE
PREMIER
FOUR SQUARE
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
FOUR SQUARE PREMIER
रु. 3.50 में 10
स्थानीय कर अतिरिक्त
वैधानिक चेतावनी : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

प्रतिक्रांतिकारी या स्वतंत्रता के योद्धा?

चीन

सत्ता-संघर्ष का नया दौर

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव तथा उदारवादी गुट के नेता हू याओ पांग की गत १५ अप्रैल को हुई मृत्यु के बाद चीन में अधिक लोकतंत्र की मांग तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के नारे के साथ जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, क्या वह पश्चिम प्रेरित था या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी तथा अनुदारवादी गुटों के बीच जारी सत्ता संघर्ष का ही परिणाम था? कट्टरपंथियों ने पार्टी के महासचिव झाओ झियांग को पद से हटा कर तथा सेना की मदद से छात्र आंदोलन को फिलहाल कुचलकर अपनी विजय का डंका तो पीट दिया है, किंतु क्या चीन में उठती अधिक लोकतंत्र की मांग सदा-सदा के लिए दफन हो गयी है?

मध्य अप्रैल '८९ से जून के प्रथम सप्ताह तक जारी रहनेवाले चीनी छात्रों के आंदोलन पर टीका-टिप्पणी करते हुए देशी-विदेशी समीक्षकों ने जुदा-जुदा नजरिया पेश किया है। जहां कुछ लोगों का यह मानना है कि १६ अप्रैल को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित थ्येन आन मन चौक पर छात्रों ने एकत्र होकर अधिक लोकतंत्र की मांग के नाम पर जिस आंदोलन की शुरुआत की वह कुछ और नहीं, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़ों के बीच सत्ता संघर्ष की परिणति थी। वहीं कुछ समीक्षकों की राय है कि चीनी छात्रों द्वारा अधिक लोकतंत्र की मांग १९७९ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर संभालने वाले चीन के सर्वोच्च नेता ८४ वर्षीय दंग श्याओ पंग द्वारा आर्थिक सुधार के नाम पर अपनायी गयी 'खुलेद्वार' की नीति का परिणाम है। कुछ भी हो इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगभग सात सप्ताह तक शांतिपूर्ण ढंग से चले छात्र आंदोलन को ४ जून को चीन की जनमुक्ति सेना ने जिस बर्बरता के साथ कुचला है, उससे यह साफ हो जाता है कि माओत्से तंग की क्रांतिकारी विचारधारा तो चीन को पूर्णत: 'लाल' न कर सकी, किंतु दंग श्याओ पंग ने अधिक आजादी की गुहार कर रहे छात्रों का खून बहाकर चीन को 'लाल' करने की कसम अवश्य खायी थी।

रूसी सुधारवाद की हवा : गोर्बाचेव, दंग तथा रईसा

अमरीकी प्रेरणा : लोकतंत्र की देवी की प्रतिमा

फिलहाल पराजय : विजय की कामना करती एक छात्रा

आंदोलन १६ अप्रैल से ही क्यों ? : जो लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं कि चीनी जनता, खासतौर से चीन के छात्र प्रतीकों के माध्यम से अपनी लड़ाई को शुरू करना शुभ मानते हैं, उन्हें यह बात समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी कि पेइचिंग विश्वविद्यालय के छात्रों ने १६ अप्रैल को ही सैकड़ों-हजारों की संख्या में एकत्र होकर अधिक लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलन क्यों शुरू किया ? जाहिर है, थ्येन आन मन चौक की ऐतिहासिक मीनार से टिका कर छात्रों ने जिस नेता की प्रतिमा रखी थी, वह सचमुच चीन में सुधार का पक्षधर था। शायद इसीलिए दो वर्ष पूर्व छात्रों के प्रति उसकी हमदर्दी की भनक पाकर सुधारवादी धड़े के नेता होने के बावजूद दंग श्याओ पंग ने उसे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद से हटाया था। उस नेता का नाम था हू याओ पांग, जिसकी १५ अप्रैल को ही मृत्यु हुई थी। वैसे तो चीन में यह खबर फैलायी गयी थी कि पांग दिल का दौरा पड़ने से मरे, किंतु हांगकांग से मिली कुछ खबरों में यह बताया गया कि अंतिम समय में

रंग लायेगा ? : जनमुक्ति सेना की मार के घायल युवक

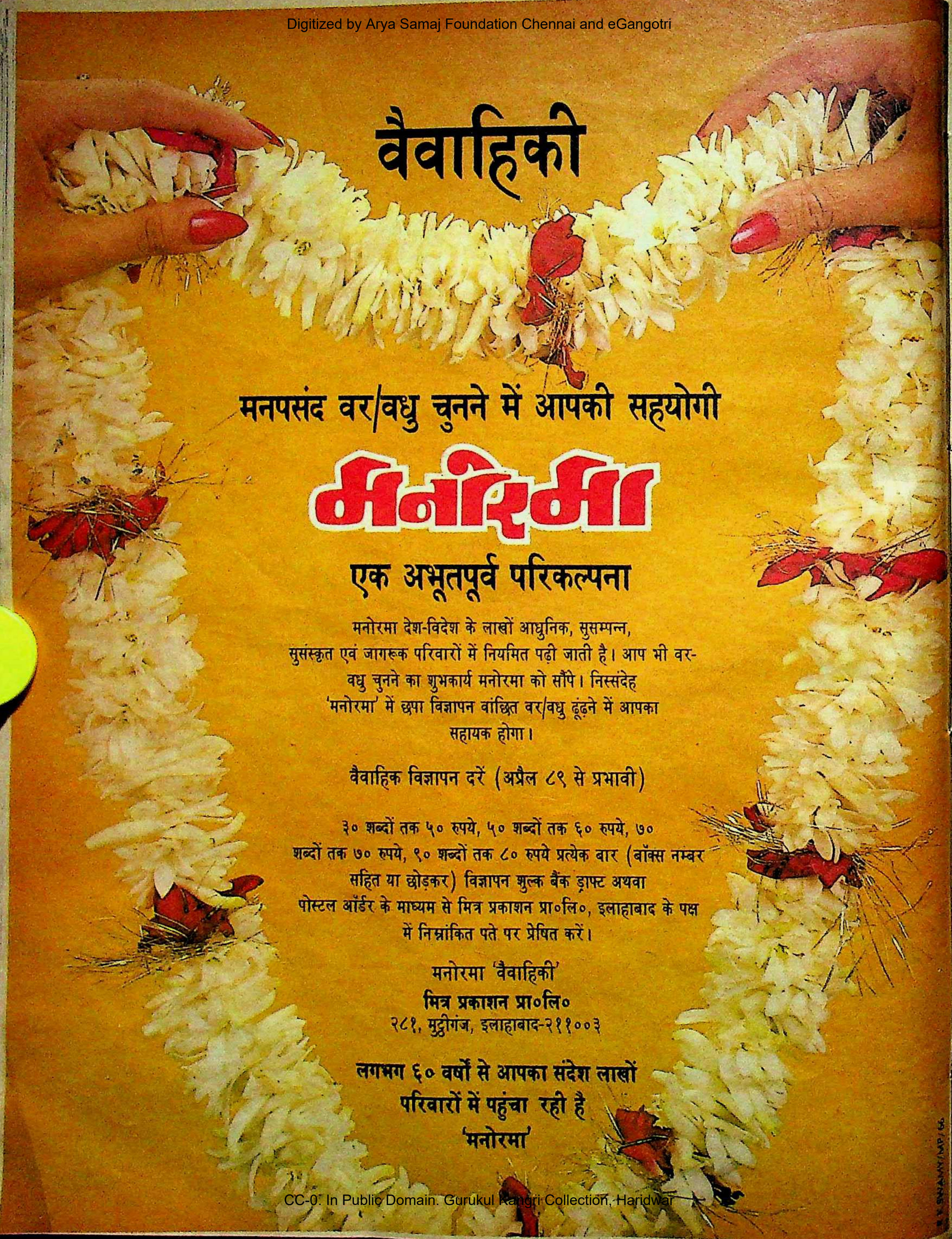

वैवाहिकी

मनपसंद वर/वधु चुनने में आपकी सहयोगी

मनोरमा

एक अभूतपूर्व परिकल्पना

मनोरमा देश-विदेश के लाखों आधुनिक, सुसम्पन्न, सुसंस्कृत एवं जागरूक परिवारों में नियमित पढ़ी जाती है। आप भी वर-वधु चुनने का शुभकार्य मनोरमा को सौंपे। निस्संदेह 'मनोरमा' में छपा विज्ञापन वांछित वर/वधु ढूंढ़ने में आपका सहायक होगा।

वैवाहिक विज्ञापन दरें (अप्रैल ८९ से प्रभावी)

३० शब्दों तक ५० रुपये, ५० शब्दों तक ६० रुपये, ७० शब्दों तक ७० रुपये, ९० शब्दों तक ८० रुपये प्रत्येक बार (बॉक्स नम्बर सहित या छोड़कर) विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से मित्र प्रकाशन प्रा०लि०, इलाहाबाद के पक्ष में निम्नांकित पते पर प्रेषित करें।

मनोरमा 'वैवाहिकी'
मित्र प्रकाशन प्रा०लि०
२८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३

लगभग ६० वर्षों से आपका संदेश लाखों परिवारों में पहुंचा रही है 'मनोरमा'

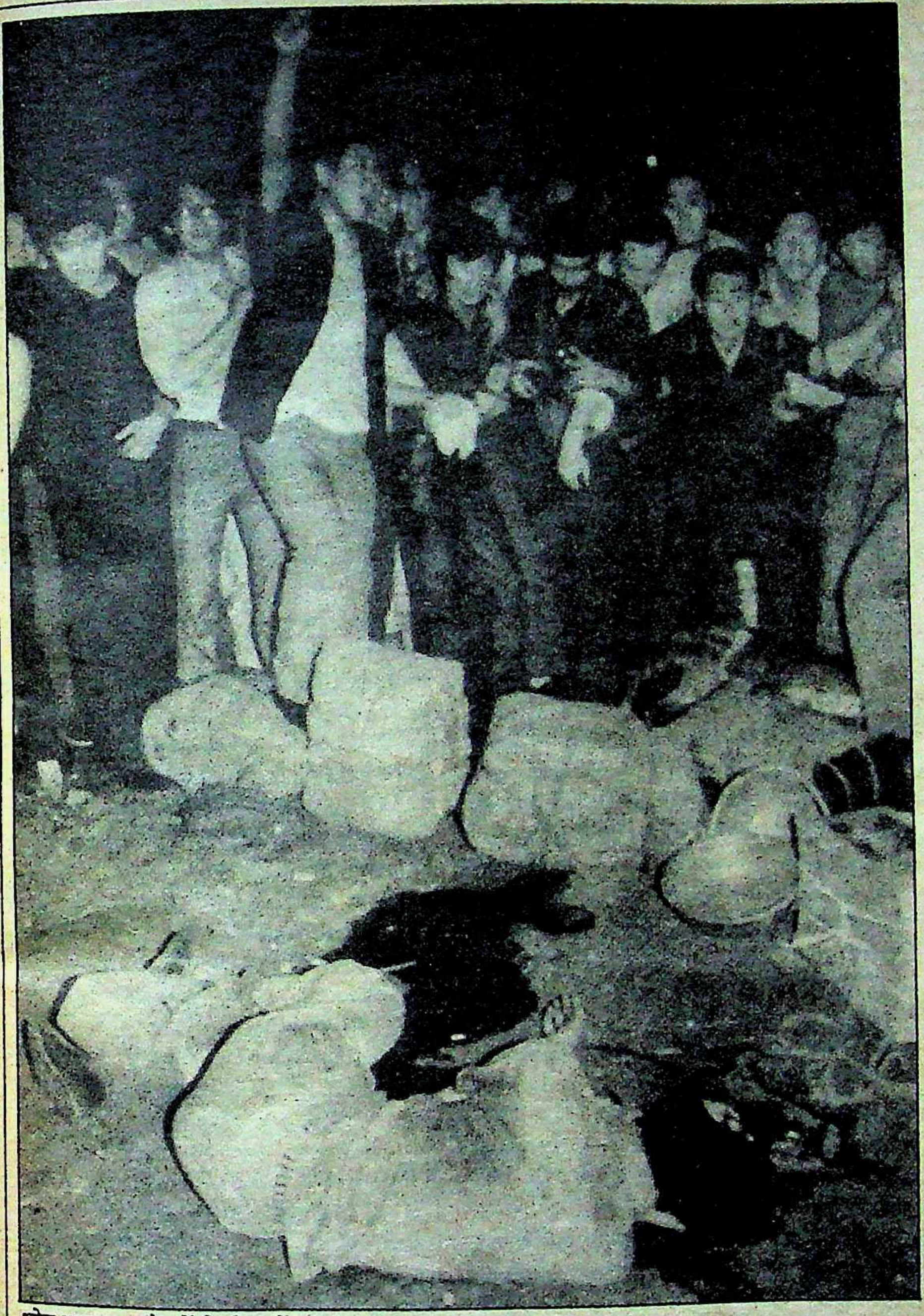

थ्येन आन मन चौक में बिछी लाशें

अनिवार्य चिकित्सकीय व्यवस्था में लापरवाही करके उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए सुला दिया गया। सचाई जो भी हो, किंतु यह भ्रम तो पैदा हो ही गया कि पांग अपनी छात्र-समर्थक विचारधारा के कारण मारे गये। बस फिर क्या था, अपने मृत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्र पांग की प्रतिमा के साथ थ्येन आन मन चौक पर एकत्र होने लगे। देखते-देखते थ्येन आन मन चौक विश्वविद्यालय के छात्रों से घिर गया। जाहिर है, छात्रों की पांग को इससे बेहतर श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी कि उन्होंने एकजुट होकर अधिक लोकतंत्र की मांग का बिगुल बजा दिया और चीन में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवाज बुलंद कर दी।

आंदोलन का उत्प्रेरक : जब बात चीनी छात्रों के संघर्ष के प्रतीकों की ही चल पड़ी है, तो प्रतीकों के तार-से-तार जोड़ने पर कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं, जिनको नजरअंदाज करने से छात्र आंदोलन के उद्देश्यों की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकती। हू याओ पांग की मृत्यु तो छात्रों को प्रेरणा देने में सहायक हुई ही, १७ मई को चीन की सरकारी यात्रा पर आने का सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यक्रम भी इस आंदोलन का सब महत्वपूर्ण प्रेरक था। जाहिर है, जिस समाजवादी नेता ने विश्व के सबसे बड़े समाजवादी देश रूस में 'ग्लास्तनोस्त' तथा 'पेरेस्त्रोइका' का प्रयोग शुरू किया। उसकी चीन यात्रा पर अधिक लोकतंत्र की मांग करने वाले चीनी छात्रों का उत्साहित होना लाजिमी था। शायद इसीलिए आंदोलनरत छात्रों ने इस बात की घोषणा भी की थी कि वे सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का थ्येन आन मन चौक पर स्वागत करेंगे तथा उनसे उनके सुधारवादी कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे।

यही नहीं, १६ अप्रैल से 'अधिक लोकतंत्र' की मुनादी करके आंदोलन छेड़नेवाले छात्रों के सामने ४ मई का वह ऐतिहासिक दिन भी था, जब ७० वर्ष पूर्व छात्रों ने ही साम्राज्यवाद के खिलाफ बिगुल बजाया था तथा राष्ट्रवाद की सुरक्षा का नारा बुलंद किया था। ४ मई, १९१९ को छिड़े छात्र आंदोलन के कारण ही चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसने आगे चलकर चीन की सत्ता अपने हाथों में ली। इसलिए यह कहना भी अनुचित न होगा कि ४ मई को चीन के प्रमुख छात्र आंदोलन की ७०वीं वर्षगांठ के मौके को भी चीनी छात्रों ने अपना प्रतीक बनायां।

आंदोलन शैली : बहरहाल, १६ अप्रैल को सैकड़ों की तादाद में थ्येन आन मन चौक पर एकत्र हुए छात्रों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती गयी। सैकड़ों की भीड़ हजारों के हुजूम में तब्दील होने लगी। जो आंदोलन शुरू में पेइचिंग के छात्रों तक ही सीमित था, वह देखते-देखते संपूर्ण चीन के छात्रों का आंदोलन बन गया। पेइचिंग के आसपास के क्षेत्रों के छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए थ्येन आन मन चौक पर एकत्र होने लगे। आंदोलनकारियों में लड़कों की संख्या तो अधिक थी ही, किंतु लड़कियों ने भी अपनी शक्ति का इजहार करने में अपने आपको पीछे नहीं रखा था। मजे की बात तो यह थी कि दिन भर तो छात्र अपने बैटरीचालित लाउडस्पीकरों के जरिये अपनी मांगें जनता के सामने रखते तथा अपने आंदोलन के तर्कसंगत होने की बातें करते ही थे, सांझ ढले भी वे थ्येन आन मन चौक नहीं छोड़ते थे। वह तो जब काफी अंधेरा होने लगता, तब छात्र नेताओं के कहने पर ज्यादातर छात्र अपने-अपने घरों को वापस चले जाते तथा छात्रों की एक टुकड़ी पूरी रात थ्येन आन मन चौक पर डटी रहती। सवेरा होते ही फिर छात्र जुटना शुरू हो जाते और दोपहर होते-होते हजारों की तादाद में छात्र थ्येन आन मन चौक पर एकत्र होकर आजादी के नारे बुलंद करते।

छात्रों के इस अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने चीनी जनता की दबी-कुचली आजादी की चाह को जिंदा कर दिया। नतीजतन २८ अप्रैल का थ्येन आन मन चौक का दृश्य चीन के वर्तमान नेतृत्व के लिए चुनौती बन गया। जिस आंदोलन को महज प्रति-क्रांतिकारी छात्रों का 'पागलपन' और 'लफंगई' मानकर चीनी नेतृत्व नजरअंदाज कर रहा था, उसके साथ चीनी जनता के सहयोग को हुकूमत ने

एक बड़ा खतरा माना। २८ अप्रैल को २ लाख लोग थ्येन आन मन चौक पर आजादी के आंदोलन में शामिल हो गये। शामिल होने वालों में पेइचिंग के हजारों कर्मचारी तथा नागरिक भी थे।

निर्णायक दौर : मजे की बात तो यह है कि अब तक जो चीनी जनता तमाशाबीन बनकर छात्रों के नारे सुनती थी, २८ अप्रैल से वह भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बन गयी। २६ अप्रैल को मिलनेवाली खबरें और भी खतरनाक थीं। पेइचिंग से प्राप्त खबरों के अनुसार जियान और चैंग्शा में भी छात्र आंदोलन शुरू हो गया था। हांगकांग के समाचार पत्रों ने चीन के २० नगरों में आंदोलन शुरू होने की खबर छापी थी। जाहिर है, ऐसे में सरकार का खामोश बैठना अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करना था। हालांकि उस दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव झाओ झियांग दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। छात्र आंदोलन के बढ़ जाने के बावजूद चीनी नेतृत्व ने झाओ झियाग को वापस बुलाना बेहतर नहीं समझा। अलबत्ता २५ अप्रैल को पोलितब्यूरो के सदस्यों की बैठक जरूर हुई, ताकि छात्र आंदोलन पर विचार-विमर्श हो सके। इस बैठक में दंग श्याओ पंग से सलाह मांगी गयी। दंग तो छात्रों की 'लफंगई' से जले-भुने बैठे ही थे, वे आगबबूला हो उठे और 'चंद लफंगों' को मजा चखाने की राय दे बैठे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "शांति और स्थिरता के दुश्मनों को कुचलकर रख दिया जाये। यदि थोड़ा बहुत खून बहता है, तो चीन को नुकसान नहीं होगा।" बैठक के तुरंत बाद दूसरे दिन पोलितब्यूरो की तरफ से छात्रों को सख्त चेतावनी जारी कर दी गयी।

छात्रों को जो नागवार गुजरा : चीनी शासन के मुख पत्र 'पीपुल्स डेली' के संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया, "अवैध संगठन बनाना अथवा अवैध प्रदर्शन करना चीनी नियमों के खिलाफ है। यही नहीं, जनता को शासन के खिलाफ भड़काना भी दंडनीय है। हू याओ पांग की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने पेइचिंग में पार्टी तथा नेताओं के खिलाफ अफवाहें फैलायी हैं तथा जनता को इस बात के लिए उकसाने की कोशिश की है कि वे शासकीय मुख्यालय में घुस पड़ें और 'कम्युनिस्ट पार्टी के अंत' के नारे लगायें।" संपादकीय में यह भी लिखा गया, "छात्रों के पागलपन' ने समाजवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया है जो देश के हित में नहीं। यही नहीं, जनता के मन में जहर घोलने तथा राष्ट्र की स्थिरता को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। शासन छात्रों की जायज मांगों, जैसे भ्रष्टाचार का अंत करना और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के पक्ष में है तथा ये मांगें कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही पूरी हो सकती हैं।" 'पीपुल्स डेली' के इस संपादकीय के बावजूद आंदोलन थमा नहीं। नतीजतन २०,००० सैनिक तथा हथियारबंद पुलिस जवान करीब के प्रांतों से पेइचिंग लाये गये। सेना की आमद से ऐसा लगा कि शीघ्र ही आंदोलन का अंत करने के लिए सैनिक छात्रों पर टूट पड़ेंगे, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेना तथा हथियारबंद पुलिस सिर्फ इसलिए पेइचिंग में तैनात की गयी थी, ताकि छात्र काबू में रहें और कोई अप्रिय घटना न घटने पाये।

सीधा टकराव : जनमुक्ति सेना और छात्र

'पीपुल्स डेली' के संपादकीय के जरिये छात्रों को जो चेतावनी दी गयी थी तथा उन पर जो आरोप लगाये गये थे, उससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। उसे शात करने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली फंग ने छात्रों से क्षमायाचना की तथा पेइचिंग कम्युनिस्ट पार्टी की म्युनिसिपल ब्रांच के नेताओं तथा म्युनिसिपल शासकों ने एक छात्र संगठन के २५ प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। उल्लेखनीय है कि कम्युनिस्ट नेताओं ने उस छात्र संगठन से बातचीत नहीं की जो हाल में आंदोलन के दौरान बना था, न ही शासन से उसे मान्यता मिली थी। इसीलिए हाल में बने 'चीनी छात्र संगठन' को 'पीपुल्स डेली' ने अवैध संगठन कहकर पुकारा था। नेताओं की छात्रों से बातचीत विफल इसलिए हुई, क्योंकि जिस छात्र संगठन के प्रतिनिधियों से शासन ने बातचीत की, उसे थ्येन आन मन चौक पर आंदोलनरत संगठन ने मान्यता नहीं दी।

प्रचार का मौका : बहरहाल, इसी तरह दिन गुजरते गये तथा चीनी नेतृत्व और छात्रों के बीच तनाव बढ़ता गया। चूंकि १५ मई को ३० वर्षों से बिगड़े संबंधों के धागे जोड़ने के लिए सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव चीन पहुंचनेवाले थे, इसलिए ऐसे मौके पर चीनी नेतृत्व किसी तरह के हंगामे का हामी नहीं था। १३ मई को विश्व भर के लगभग एक हजार पत्रकार सोवियत-चीन शिखर सम्मेलन का जायजा लेने के लिए पेइचिंग पहुंच गये थे। पत्रकारों की इस उपस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश में १३ मई को ही थ्येन आन मन चौक पर एकत्र लाखों छात्रों में से ७०० छात्र अपनी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गये। यह भूख हड़ताल भी अजीब तरह की थी। भूख हड़ताल करनेवाले छात्रों की अलग-अलग टुकड़ियां बन गयी थीं। एक टुकड़ी उठती, तो उसकी जगह दूसरी टुकड़ी ले लेती। जाहिर है, छात्रों का मकसद दुनिया को यह जताना था कि चीन के छात्र भी आजादी का मकसद और मतलब समझने लगे हैं। साथ ही वे विश्व के सामने उस चीनी नेतृत्व की सही तस्वीर रखना चाहते थे जो अपने आपको सुधारवाद का पक्षधर तो कहता है, किंतु जब जनता राजनीतिक सुधार की बात करती है, तो बगलें झांकने लगता है। छात्रों ने जो चाहा था, बिलकुल वही हुआ। चीन-रूस शिखर बैठक का जायजा लेने गये पत्रकारों ने छात्र संघर्ष को भी बहुत करीब से देखा और चीनी जनता के असंतोष को दुनिया भर में पहुंचाने का प्रयास किया। यही नहीं, इसी दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री ली फंग तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी थी। इसके बावजूद शासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था। आखिरकार इसी हंगामे के माहौल में १५ अप्रैल को रूस में 'ग्लास्तनोस्त' और 'पेरेस्त्रोइका' के प्रयोग के लिए विख्यात नेता मिखाइल गोर्बाचेव चीन पहुंच गये। चीनी नेतृत्व ने कामरेड गोर्बाचेव की आमद पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। उल्लेखनीय है कि चीनी नेतृत्व ने शुरू में गोर्बाचेव का थ्येन आन मन चौक पर स्वागत करने का कार्यक्रम बनाया था, किंतु जब छात्र अपनी जिद से नहीं हटे तो मजबूर होकर हुकूमत को स्वागत स्थल बदलना पड़ा था। जाहिर है, यह घटना चीन के कट्टरवादी शासकों के लिए छात्रों की ओर से बहुत बड़ी चुनौती थी। किंतु कट्टरवादी नेता मौके की नजाकत का खयाल करके सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सोवियत नेता के वापस जाने की देर थी कि दंग श्याओ पंग का गुस्सा उबल पड़ा।

झाओ झियांग का इस्तीफा : 'चंद लफंगों' तथा 'शांति भंग' करनेवालों का सिर कुचलने के लिए बल प्रयोग करने का फैसला किया जाने लगा।

अपनी ही जनता को रौंद डाला

कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में उपस्थित पार्टी के महासचिव झाओ झियांग ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत छात्रों पर बल प्रयोग करने का विरोध किया, किंतु सर्वोच्च नेता दंग तथा सत्तासीन होने के लिए उनके पिछलग्गू बन चुके नेताओं ने बल प्रयोग पर सहमति दे दी। जब झाओ झियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी तथा अनुदारवादी धड़ों के मदभेद उभरकर सामने आये। जहां उदारवादी धड़ा छात्रों से बातचीत के जरिये आंदोलन समाप्त करवाने के पक्ष में था, वहीं अनुदारवादी धड़ा छात्र आंदोलन को कम्युनिस्ट नेतृत्व के लिए चुनौती मान बैठा था। सत्ता संघर्ष की लड़ाई में विजय हुई अनुदारवादी गुट की तथा १६ मई को पेइचिंग के कुछ क्षेत्रों तथा कुछ अन्य नगरों में छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए जनमुक्ति सेना मय टैंकों के भेज दी गयी।

किंतु इससे पहले कि सैनिक थ्येन आन मन चौक तक पहुंच पाते, जनता ने आगे बढ़कर सैनिकों से बातचीत शुरू कर दी। जनता ने सैनिकों को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि उनका काम जनता का दमन करना नहीं, अपितु जनता की जायज मांगों को पूरा करवाने में सहायता करना है। हजारों माताएं पेइचिंग की सड़कों पर सैनिकों से हथियार न उठाने की विनती करती देखी गयीं। जाहिर है, जिनके बेटे चीन में अधिक आजादी की मुनादी करके थ्येन आन मन चौक पर आंदोलन कर रहे थे, वे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे-बेटियों को मरते कैसे देख सकते थे। जनता अपनी कोशिश में सफल हुई। सैनिकों ने चौक की ओर बढ़ने के बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया। जनमुक्ति सेना ने यह कदम उठाकर अपने नाम की सार्थकता का विश्व में ढिंढोरा पिटवा दिया। किंतु छात्र आंदोलन को चुनौती मान चुका नेतृत्व भी सेना भेजकर चैन की नींद नहीं सो गया था। सेना की हुकुमउदूली ने स्थिति को और गभीर कर दिया। २० मई को कम्युनिस्ट पार्टी ने पेइचिंग के कुछ स्थानों में मार्शल ला लागू कर दिया। थ्येन आन मन चौक पर लाखों की तादाद में एकत्र छात्रों ने मार्शल ला का भी विरोध किया। एक तरफ सेना ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। दूसरी तरफ, छात्र आंदोलन नयी ऊंचाइयां छूने पर आमादा था। ली फंग और दंग श्याओ पंग को ऐसा लगा जैसे उदारवादियों का धड़ा उन पर हावी हो गया है। २२ मई को जनमुक्ति सेना के कुछ उच्चस्तरीय सैनिक अधिकारियों ने मार्शल ला का विरोध करते हुए छात्र आंदोलन को सहयोग करने का निर्णय ले लिया। जिन सात प्रमुख अधिकारियों ने निर्णय पर हस्ताक्षर किये थे, उनमें पूर्व रक्षामंत्री झांग एपिंग तथा जनमुक्ति सेना के भूतपूर्व प्रमुख यांग डेजी भी शामिल थे। निर्णय में स्पष्ट लिखा गया था, "जनमुक्ति सेना चीनी जनता के लिए है। वह चीन के नागरिकों की जान नहीं ले सकती।" इस बीच चीन के सर्वोच्च नेता दंग श्याओ पंग अचानक गायब हो गये। एक सप्ताह बाद जब दंग लौटे, तो पता चला कि वे उदारवादियों से मोर्चा लेने के लिए ली फंग को छोड़कर कहां चले गये थे। यह सच था कि दंग वुहान ही गये थे, किंतु आराम करने नहीं। किसी को खबर भी नहीं थी और अंदर ही अंदर उन्होंने चीन के सातों क्षेत्रीय सैनिक कमांडरों को वुहान में जमा होने की सूचना भेज दी थी। जब वे वुहान से लौटे, तो सात में से छह कमांडरों की पेइचिंग में मार्शल ला के लिए सहमति लेकर। जाहिर है, सात में से छह क्षेत्रीय कमांडरों की सहमति उदारवादी धड़े के छात्र-समर्थित नजरिये को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी थी।

दूसरी ओर, चीन में अधिक लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्र थे, जो दिन-प्रतिदिन अपने आंदोलन को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ३० मई को छात्रों ने ३० फुट ऊंची 'लोकतंत्र की देवी' की प्रतिमा थ्येन आन मन चौक पर लगी माओ की प्रतिमा के सामने लाकर खड़ी कर दी। जाहिर है, जहां लोकतंत्र की देवी की प्रतिमा छात्रों के 'लोकतंत्र प्रेम' तथा उनकी 'अमरीकी प्रेरणा' का द्योतक थी, वहीं माओत्से तंग की प्रतिमा के समक्ष उसका खड़ा किया जाना माओवाद के लिए करारा तमाचा था। इस पर भी चीनी नेतृत्व की तरफ से कोई सख्त कदम न उठाये जाने पर छात्रों को अपनी जीत का भ्रम हो आया। शायद इसीलिए उन्होंने २० जून तक थ्येन आन मन चौक पर कब्जा किये रहने की योजना बना डाली। क्योंकि २० जून को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (चीनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी) की बैठक होने वाली थी। छात्रों का इरादा था कि वे बैठक के समय अपनी मांगों पर जोर देंगे और लगभग हार मान चुका नेतृत्व उनकी बातों पर विचार करने पर मजबूर हो जायेगा। किंतु उन्हें क्या मालूम था कि वे जो कुछ सोच रहे थे, वह महज एक हसीन सपना था। चीनी नेतृत्व इसलिए खामोश नहीं था कि उसने हार मान ली थी, अलबत्ता अंदर ही अंदर छात्र आंदोलन को तार-तार कर देने की योजना तैयार की जा रही थी।

सेना की चढ़ाई : ३-४ जून की रात में ही सेना के नौजवान दंग श्याओ पंग की योजना को क्रियान्वित करने के लिए थ्येन आन मन चौक की ओर बढ़ने लगे। हथियारबंद पैदल सैनिकों के साथ टैंक भी कतार बनाकर आगे बढ़ रहे थे और सैनिकों से भरी ट्रकें आहिस्ता-आहिस्ता सामरिक व्यूह के अनुसार चौक की ओर बढ़ रही थीं। देखकर ऐसा लगता था, मानो सीमा पर दुश्मन की ललकार का जवाब देने के लिए जनमुक्ति सेना कमर कसकर आगे बढ़ रही हो। छात्रों को आज भी यह भ्रम था कि सेना उनकी ओर बढ़ जरूर रही है, किंतु उनके मनाने-समझाने पर वह पुनः वापस चली जायेगी। जाहिर है, उन्हें क्या पता था कि ८४ वर्षीय दंग ने १३वीं पार्टी कांग्रेस के समय पार्टी के पोलितब्यूरो से तो अपने आपको अलग कर लिया था, किंतु केंद्रीय मिलिटरी आयोग की अध्यक्षता का पद अपने से अलग नहीं किया था। इसी पद का इस्तेमाल करके दंग ने वुहान में क्षेत्रीय सैनिक कमांडरों की बैठक बुलायी थी और उनसे मार्शल ला की सहमति प्राप्त कर ली थी। जिसकी परिणति यह थी कि आज जो सेना थ्येन आन मन चौक की ओर बढ़ रही थी, वह चीनी शासन के सख्त आदेशों का पालन कर रही थी। आज फिर छात्र सेना को अपने पक्ष में करने के लिए साहस जुटा रहे थे कि तभी टैंकों ने आग बरसानी शुरू कर दी। सैनिकों के हाथों में चीनी समाजवाद की प्रतीक बनी एके-४७ राइफलों ने छात्रों को निशाना बनाना शुरू किया और थ्येन आन मन चौक की ओर सैनिक बिना रुके हुए बढ़ते गये। पलक झपकते ही कूड़े के ढेर पर लाशों के अंबार लगने लगे और जो छात्र अपनी जान बचाने में सफल हुए, वे सेना की दरिंदगी से डर कर चौक छोड़कर भागने लगे। सेना ने चौक में दाखिल होकर

'लोकतंत्र की देवी' की प्रतिमा को गोलियों से छलनी कर दिया और दुनिया के आजाद मुल्कों को यह बता दिया कि चीनी समाजवादी नेतृत्व 'पश्चिमी तर्ज की आजादी' को आज भी सहन करने के पक्ष में नहीं।

सैनिक दरिंदगी : दूसरे दिन बाहरी देशों के अखबारों के पहले पन्ने चीन की सैनिक दरिंदगी के वर्णन से भरे पड़े थे। कोई लिखता दस हजार नौजवान आजादी की मांग करते हुए शहीद हुए, तो कोई कहता २० हजार नौजवानों ने आजादी की चाह में अपनी कुर्बानी दे दी। अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश ने तो कड़े शब्दों में सैनिक कार्यवाही की भर्त्सना की। अमरीका और ब्रिटेन दोनों ने चीन को सैनिक सामान बेचने पर पाबंदी लगा दी। किंतु सेना ने सबकी बातें अनसुनी करते हुए अपनी कार्यवाही जारी रखी। छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गये। छात्र संगठनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी। कई हजार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और आठ लोगों को फांसी पर चढा दिया गया। बागियों की धर-पकड़ तेज करने के लिए प्रांतीय सीमाओं पर सेना की चौकसी बढ़ा दी गयी। चीन से बाहर जाने वाली सीमाओं को भी सील कर दिया गया। स्थिति यह हो गयी कि सड़कों पर श्मशानी सन्नाटा छा गया। जिधर छात्रों की टुकड़ी नजर आती, टैंकों से उन्हें भून दिया जाता। इस बीच यह भी खबर आयी कि कुछ स्थानों पर २७वीं और ३८वीं सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। सैकड़ों सैनिकों के आपसी मुठभेड़ में मारे जाने की भी खबर गर्म हुई। छात्रों को कुचलने का काम २७वीं सेना ने ही किया था। किंतु ३६ घंटे के बाद पेइचिंग की समाचार एजेंसियों ने राजधानी मे स्थिति नियंत्रण में होने की खबर देनी शुरू कर दी।

छात्र-आंदोलन का इतिहास : जहां तक चीन में छात्र आंदोलनों के इतिहास की बात है, यह कहना गलत न होगा कि छात्र आंदोलनों का चीनी इतिहास बहुत पुराना है। १९१९ में छात्रों ने सुधार और स्वतंत्रता की ऐसी मांग की थी कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था। छात्र आंदोलन छिड़ने के दो वर्ष बाद ही चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। १९६६ से १९७६ के बीच के दस वर्षों में माओ ने देश की युवा शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि, सांस्कृतिक क्रांति का इस्तेमाल चीन के शासकों ने गलत उद्देश्य के लिए किया। जब युवा शक्ति को असलियत का पता चला, तो चाओ एन लाई की मृत्यु के बाद छात्र एक बार फिर चीनी शासकों के खिलाफ खड़े हुए थे। चाओ की समाधि पर अनगिनत छात्रों ने खून बहाया था, जो व्यर्थ नहीं गया। १९७६ में माओ की मृत्यु के बाद दंग श्याओ पंग ने इसी जनशक्ति का सहारा लेकर चौकड़ी को निष्प्रभावी करके सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सामुदायिक खेती की परंपरा समाप्त कर दी गयी और उद्योगों में निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया। चीन के उदारवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व ने शुरू में साम्यवाद को मानवतावादी शक्ल प्रदान करने के काम किये। यही नहीं, पश्चिम के साथ संबंधों की नयी शुरुआत करके इन नेताओं ने दुनिया के अन्य समाजवादी देशों को अपनी घरेलू और विदेश नीति में 'नयी शुरुआत करने के प्रेरणा दी।

सत्ता संघर्ष : किंतु किसे पता था कि सुधारों की नयी शुरुआत चीन के समक्ष विषम परिस्थितियां खड़ी कर देगी। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए अर्थतंत्र को खुला छोड़ देने की छूट तो दी गयी, किंतु एक निश्चित सीमा तक सुधार के बाद शासकों को यह महसूस हुआ कि समाजवादी व्यवस्था आर्थिक तरक्की का रास्ता रोककर खड़ी हो गयी है। यह भी महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक सुधार के बिना आर्थिक पुनर्गठन संभव नहीं है। नतीजतन राजनीतिक सुधार की मांग उन क्षेत्रों में जागी जो काफी पिछड़े थे। जब दंग श्याओ पंग के आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों ने चीन के समक्ष नयी परेशानियां खड़ी करनी शुरू कीं, तो जिन कट्टरपंथियों को दंग ने दबा रखा था वे सिर उठाने लगे। फिर दंग श्याओ पंग की बढ़ती उम्र और उत्तराधिकारी की उनकी खोज के कारण उत्पन्न स्थिति ने भी कट्टरपंथियों को आगे आने का मौका दिया। नतीजतन आर्थिक विकास से अर्थतंत्र के गरमाने, मुद्रास्फीति और राजनीतिक सुधार की मांग बढ़ने से कट्टरपंथियों को यह कहने का मौका मिला कि सुधारों की मांग के पीछे समाजवाद को समाप्त करके पूंजीवाद को स्थापित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब दंग ने यह महसूस किया, तो अपनी कुरसी बचाये रखने के लिए उन्हें कट्टरवादी रुख अख्तियार करना पड़ा। जाहिर है, राजनीतिक सुधार का प्रयोग इतना सरल नहीं था। फिर उदारवादियों और अनुदारवादियों के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा था, वह भी तो चीनी समाजवाद के लिए बहुत बड़ी चनौती था।

> समाजवादी देशों में
> तो जो परिवर्तन हो रहे हैं, सो हैं
> ही, पिछले तीन वर्षों में
> चीन के गैरसमाजवादी पड़ोसी देशों में
> आजादी की जो हवा बही है,
> उसका असर भी चीन तक पहुंचना
> लाजिमी है। पाकिस्तान,
> बर्मा, फिलीपींस तथा दक्षिण कोरिया
> में जिस तेजी के साथ लोकतंत्र की
> स्थापना हुई या जहां आजादी की मुहिम
> चल रही है, क्या उसे नजरअंदाज
> किया जा सकता है ? ऐसे
> में चीनी जनता की भावनाओं की कद्र
> करने के बजाय उसको कुचलकर शासन
> करना क्या तर्कसंगत कहला
> सकता है ?

उपर्युक्त इतिहास को मद्देनजर रखते हुए यदि यह कहा जाये कि अप्रैल-मई में छात्रों ने थ्येन आन मन चौक पर जिस आंदोलन की शुरुआत की वह चीनी नेतृत्व के ही उदारवादी गुट की प्रेरणा की परिणति थी तथा उस आंदोलन का बीज दंग श्याओ पंग के सुधारवादी कार्यक्रमों ने ही बोया था, तो गलत न होगा। फिर चीनी जनता, विशेषकर छात्रों के समक्ष अन्य समाजवादी देशों में हो रहे परिवर्तनों की भी तो मिसालें हैं। यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड तथा सोवियत रूस में जिस तरह से राजनीतिक सुधार के कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं तथा समाजवादी लोकतंत्र की जमीन मजबूत की जा रही है क्या चीनी जनता उससे प्रेरित नहीं होगी ? समाजवादी देशों में तो जो परिवर्तन हो रहे हैं, सो हैं ही, पिछले तीन वर्षों में चीन के गैरसमाजवादी पड़ोसी देशों में आजादी की जो हवा बही है, उसका असर भी चीन तक पहुंचना लाजिमी है। पाकिस्तान, बर्मा, फिलीपींस तथा दक्षिण कोरिया में जिस तेजी के साथ लोकतंत्र की स्थापना हुई या जहां आजादी की मुहिम चल रही है, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है ? ऐसे में चीनी जनता की भावनाओं की कद्र करने के बजाय उसको कुचलकर शासन करना क्या तर्कसगत कहला सकता है ?

आसार नयी क्रांति के : बजाहिर ऐसा जरूर लग रहा है कि सरकार ने 'प्रतिक्रांतिकारियों' को काबू में कर लिया है, किंतु ४, ५ तथा ६ जून की सैनिक बर्बरता ने चीन के नेतृत्व के प्रति चीन की जनता के मन में जो जहर घोला है, वह मौका पाते ही चीनी सत्ता को हिलाने के लिए पुनः उबल पड़ेगा। फिर आंदोलन से पूर्व चीनी अर्थव्यवस्था के समक्ष जो संकट थे, सो तो थे ही, राजनीतिक उथल-पुथल तथा छात्र असंतोष भड़कने तथा उसको दबाये जाने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, वह भी चीनी शासकों के लिए काफी खतरनाक है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि व्यापार में घाटा बढ़ेगा तथा घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी होगी। मुद्रास्फीति और महंगाई भी चरम पर पहुंच जायेगी। यही नहीं, 'प्रतिक्रांतिकारियों' के प्रति जिस तरह की कार्यवाही शुरू हुई है, उससे जरूरी आर्थिक सुधारों में रुकावट पैदा होगी। नतीजतन विदेशी ऋणों तथा पूंजीनिवेशों में कमी आयेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और खाने-पीने की वस्तुएं प्राप्त करने में दिक्कतें सामने आयेंगी।

इसलिए आनेवाले दिनों में चीन में क्या परिवर्तन होंगे, यह नहीं बताया जा सकता, किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि चीन के नेतृत्व ने 'प्रतिक्रांतिकारियों' के प्रति रवैये में नरमी नहीं की, तो वह दिन दूर नहीं, जब चीन के छात्र वर्तमान शासन को ही प्रतिक्रांतिकारी घोषित करके नयी क्रांति का बीड़ा उठा लेंगे।

—रामपाल सिंह; तारिक खान

जापान

प्रधानमंत्री का परकीया प्रेम

जापान के नये प्रधानमंत्री सोसुके उनो तीन साल पहले की अपनी रंगरेलियों के भंडाफोड़ के कारण मुश्किल में फंस गये हैं। मध्य जून में विपक्षी नेताओं ने जापान की संसद में लगातार दो-तीन दिनों तक इन लफड़ों पर शोर मचाकर मामले को आम चर्चा का विषय बना दिया। प्रधानमंत्री सोसुके उनो जिस औरत के साथ तीन साल पहले चार महीने तक मजे लूटते रहे, वह एक बहुचर्चित 'गीशा' बतायी जाती है। जापान के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक नेता की अपनी वैध पत्नी (६४ वर्षीय चियो) से दगाबाजी पर देश की संसद में खुली बहस छिड़ी है।

आज की दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष की ऐयाशी का यह पहला किस्सा नहीं है। यूनान के ७० वर्षीय प्रधानमंत्री पापेंद्रू ३५ वर्षीय विमान परिचारिका दिमित्रा लियानी से ब्याह रचाने के फैसले के साथ अपनी ६६ वर्षीय अमरीकी पत्नी मार्गरेट को त्याग कर व्यापक चर्चा के विषय बने हुए हैं। आस्ट्रेलिया के ५९ वर्षीय प्रधानमंत्री बाब हाक अपनी पत्नी हेजेल से दगाबाजी कर ३२ वर्षों तक दूसरी सुंदरियों के साथ सहवास करते रहे, जबकि इनकी शादी के ३३ साल ही बीते थे। इसी तरह ६६ वर्षीय प्रधानमंत्री उनो पर एक 'गीशा' रखने का आरोप लगाया जा रहा है। जापान में 'गीशाओं' को परंपरा से नगरवधुओं जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। जापानी रईसों में वे देश की 'जातीय मिथक की महिमामयी थाती' मानी जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री काकुई तनाका ने तो एक गीशा के साथ बेटे-बेटियों से भरा बाकायदा एक समानांतर परिवार ही बसा रखा था।

प्रधानमंत्री उनो के जिस अज्ञात महिला से कथित लफड़े रहे हैं, उसने खुद भेद खोल दिया है। बेशक इससे उनो की प्रतिष्ठा गिरी है। लेकिन जापान में, खासकर राजधानी टोकियो में, लोगों की आम धारणा यह है कि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी फजीहत यह नहीं है कि वे अपनी पत्नी के लिए दगाबाज आदमी के रूप में जाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी तौहीन एक ऐसे 'कंगाल ऐयाश' के रूप में चर्चित होना है जो अपनी प्रेयसी को इतनी रकम नहीं दे पाता कि वह अपना मुंह बंद रखे। लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका 'संडे मैनिची' के जून के दूसरे हफ्तेवाले अंक में छपी एक कहानी के अनुसार उनो का यह गुप्त प्रेम-प्रकरण ४० वर्ष की एक सुंदरी के साथ चलता रहा है। यह महिला पहले सचिव रह चुकी है और एक साल तक 'गीशा' के तौर पर धंधा करती रही है। उनो ने उसे प्रति माह १,३०० पौंड के बराबर धन देकर संक्षिप्त सूचना पर किसी भी समय उसको हमबिस्तर बनाने का सौदा किया था। रंगरेली की शुरुआत उनो ने अपनी इस जानेमन को ९००० पौंड की रकम बतौर भेंट देकर की थी। अखबार 'असाही शिबुन' के अनुसार उनो अपनी गीशा को कुल ३० लाख येन (२०,२७० डालर) दे चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने यह लफड़ा तोड़ा, तब उक्त सुंदरी को वह रकम नहीं दी, जो देने का वायदा वे कर चुके थे। वायदे की रकम दिये बगैर नाता तोड़ लेना जापान में गीशा और आशिक के बीच परंपरा से निभाये जा रहे अनलिखे नियम का उल्लंघन है, और उनो की छीछालेदर का यही प्रमुख कारण है।

पत्रिका ने वादाखिलाफी का शिकार हुई उक्त गीशा (जिसे 'मिस ए' नाम दिया गया है) की भेंटवार्ता छापी है जिसमें कहा गया है कि उनो अपनी माशूका को भेंट देने में भी चिरकुटपन दिखाते रहे। 'मिस ए' का कहना है, "उनो महाशय ने मुझे एक कोट खरीद देने का वायदा किया, पर खरीदा कभी नहीं। वे एक अनैतिक आदमी हैं और सोचते हैं कि पैसे से औरत को खरीद सकते हैं। एक रात जब मैं टोकियो के विलासपूर्ण 'होटल न्यू ओतानी' में उनके साथ थी, तब उनकी हेकड़ी से इतनी अपमानित हुई कि मैं सो न पायी और रात भर छत ताकती रही।"

उनो ने इन अखबारी खबरों की न तो पुष्टि की और न खंडन किया है। डाइट (संसद) में विपक्षी आक्षेपों और दलीलों के जवाब में वे सिर्फ यह कहकर कतरा गये कि "यह निजी मामला है, इसे मैं सार्वजनिक बहस में डालना नहीं चाहता।" उनो के इस कथित लफड़े की बाबत उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की भी नींद हराम हो गयी है। पार्टी की संसदीय नीति समिति के एक निदेशक का कहना है, "प्रधानमंत्री के इस सेक्स स्कैंडल में हाथ होने का मामला इस कारण बड़ा नुकसानदेह बन गया है, क्योंकि रिक्रूट घोटाले के दुष्परिणामों से पार्टी को अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है।" पार्टी ज्यादा चिंतित इस कारण है कि महिलाओं में इस लफड़े की भयंकर प्रतिक्रिया हुई है। उनो का सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान 'संडे मैनिची' की रिपोर्ट में उनो पर लगाये गये अधिकांश आरोपों के 'वाशिंगटन पोस्ट' में छप जाने से हुआ है, क्योंकि इससे यह 'प्रेम कथा' दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गयी। एक विपक्षी सांसद का आरोप है, "उनो ने अपनी इस कारगुजारी से विश्व में जापान की साख मिट्टी में मिला दी है।" राजनीतिशास्त्री क्रेंजो उचिदा के अनुसार इस घोटाले से उनो का राजनीतिक खोखलापन बेपर्द हो गया है, "उनो रिक्रूट घोटाले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री इसलिए बनाये गये, क्योंकि इन्होंने दूसरे नेताओं की तरह निगमों से मोटी-मोटी रकमें नहीं लीं। इसी कारण अपनी रखैल को देने के लिए जितने धन की जरूरत थी, उतना उनके पास नहीं था।"

कुल मिलाकर, उनो का यह बेवफाई भरा लफड़ा जापानवासियों, खासकर सत्तारूढ़ एलडीपी को बड़ा नागवार गुजरा है। पार्टी के संस्थापक बुकिची मिची पर जब एक विरोधी ने सात औरतें रखने का आरोप लगाया, तब उन्होंने अपने विरोधी को डपटते हुए कहा था, "यह सही है, पर मैं सातों को पूरी तरह खुश और संतुष्ट रखता हूं।" उनो की विडंबना यह है कि वे यह दावा भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनके पांव तले की जमीन खिसक रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक छवि और सत्ता दांव पर लग गयी है।

—विदेशी डेस्क से, वशिष्ठ

> **उनो का यह बेवफाई भरा लफड़ा जापानवासियों, खासकर सत्तारूढ़ एलडीपी को बड़ा नागवार गुजरा है।**

बेनजीर की अमरीका यात्रा

२ दिसंबर, १९८८ को जब ग्यारह वर्षों के संघर्ष के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हुआ और ३५ वर्षीय बेनजीर भुट्टो विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला की हैसियत से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं, तो कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने बेनजीर की 'राजनीतिक अपरिपक्वता' को उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। बाद में राजनीतिक उथल-पुथल को मद्देनजर रखते हुए पर्यवेक्षकों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि 'बेनजीर शासन' ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। किंतु बेनजीर भुट्टो पर ऐसी टिप्पणियों का कोई खास असर हुआ नहीं दीखता। क्योंकि जिस राजनीतिक आत्मविश्वास के साथ बेनजीर अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रही हैं, वह मामूली नही। जाहिर है, पंजाब के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के शक्तिशाली विरोध और धार्मिक शक्तियों की साजिशों का सामना करना किसी 'राजनीति में सिफर' नेता के बस की बात नहीं। फिर हाल में सेना के गुप्तचर प्रमुख हमीद गुल की कुरसी छीनकर भी उन्होंने उन शक्तियों के कान खड़े कर दिये हैं जो पाकिस्तानी लोकतंत्र को घात लगाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

बेनजीर भुट्टो

घर के विरोध और अवरोध का सामना करना तो एक तरफ है, अंतरराष्ट्रीय हमदर्दी हासिल करने की उनकी ललक भी कोई ढंकी-छिपी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तुर्की तथा चीन की सफल सरकारी यात्रा के पश्चात ५ जून को अमरीका पहुंचकर बेनजीर भुट्टो ने विश्व राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उल्लेखनीय है कि स्व० जनरल जिया-उल-हक के जमाने में ही कहूटा संयंत्र की अमरीकी जांच को लेकर पाकिस्तान-अमरीका संबंधों में दरार पड़ने लगी थी। किंतु सत्ता-परिवर्तन की भनक पाकर अमरीका ने कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं किया था। इतना जरूर है कि बेनजीर के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरीका बार-बार ऐसे बयान जारी करता था जिससे लगता था कि पाकिस्तान को मिलनेवाली अमरीकी सैनिक तथा आर्थिक सहायता में कटौती होगी अथवा पूरी तरह बंद हो जायेगी।

जार्ज बुश

जाहिर है, सहायता बंद होने से पाकिस्तान के सामने संकट खड़ा हो जाता। नतीजतन अपने देश की 'अमरीकी निर्भरता' का जायजा लेते हुए बेनजीर ने अमरीका की हमदर्दी को खोना उचित नहीं समझा। परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी अमरीकी यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिये जिससे उनकी यात्रा सफल ही नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान-अमरीका संबंधों को नये आयाम भी मिले।

अमरीका ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए बेनजीर भुट्टो का जमकर स्वागत किया, ताकि अमरीका-विरोधी शक्तियां पाक-अमरीका संबंधों की गहराई के भ्रमजाल से निकलने न पायें। बाद में ६ जून को कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अमरीका के एटमी हथियार संबंधी संदेह का यह कहकर अंत किया, "हमारे पास न तो एटमी हथियार हैं और न हम बनाने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में एटमी हथियारों की होड़ भड़कानेवाला कोई काम नहीं करेगा।" बेनजीर के इस ऐलान का कांग्रेस के सदस्यों ने तालियों की गूंज से स्वागत किया। जाहिर है, एटमी हथियार न बनाने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता था? फिर बेनजीर की इस सफाई ने अमरीकी राष्ट्रपति के इस संदेह को धुल दिया कि पाकिस्तान अणुबम बना रहा है या बना चुका है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा यह प्रमाणित करना भी आसान हो गया कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने में प्रयासरत नहीं, ताकि अमरीकी कांग्रेस, पाकिस्तान को दी जानेवाली सहायता बंद न करे।

इसके अतिरिक्त बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए साठ एफ-१६ विमान का सौदा करने में भी सफल हो गयी हैं। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है, किंतु सूत्रों का कहना है कि सौदा हो गया है तथा अमरीका चार खेप में पाकिस्तान को विमान देने पर राजी है। यही नहीं, इस यात्रा के दौरान बेनजीर भुट्टो ने अफगानिस्तान कार्ड भी खेला। बेनजीर-बुश की बातचीत के दौरान अफगान समस्या के 'राजनीतिक हल' की बात सामने आयी है। हालांकि 'राजनीतिक हल' क्या होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ■

सलमान रुश्दी

कत्ल का फतवा बरकरार

इस बात में शक नहीं कि ईरानी धार्मिक क्रांति के नेता अयातुल्ला खुमैनी के निधन की जितनी खुशी इराकवासियों को हुई उतनी ही खुशी 'द सैटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रुश्दी को हुई होगी। जाहिर है, जिस धर्मगुरु के कत्ल के फतवे ने सलमान रुश्दी को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया था, उसके निधन पर खुशी होना स्वाभाविक है। वैसे खुमैनी के निधन पर आम धारणा भी यही बनी थी कि खुमैनी के निधन के साथ उनका फतवा भी दफन हो जायेगा। किंतु ८ जून को ईरानी संसद के अध्यक्ष हाशमी रफसंजानी ने जो बयान जारी किया था, उससे रुश्दी तथा उनके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रफसंजानी ने अपने बयान में कहा, "इस्लाम विरोधी उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रुश्दी के लिए इमाम ने जो फतवा जारी किया था, वह आज भी बरकरार है। हां, ब्रिटेन अगर ईरान से संबंध बनाना चाहता है, तो उसे समझौते का रास्ता निकालना चाहिए। ईरान खुद किसी तरह के समझौते की पहल के लिए तैयार नहीं है।"

८ जून को ही दो ब्रिटिश दैनिकों में प्रकाशित रुश्दी के उपन्यास से संबंधित समाचार भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अखबारों ने विश्वस्त सूत्रों का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि रुश्दी अपने उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' को वापस ले लेते हैं तथा उपन्यास का प्रकाशन बंद हो जाता है और अब तक 'सैटेनिक वर्सेज' की बिक्री से उन्हें जो फायदा मिला है, यदि वे उसको उन परिवारों में बांट देते हैं जिनके सदस्य पुस्तक का विरोध करते हुए मरे हैं, तो ईरान फतवा वापस ले सकता है। अखबारों में यह भी लिखा गया है कि इस तरह का संकेत उन्हें ईरानी मजलिस के ही महत्वपूर्ण लोगों से मिला है।

सलमान रुश्दी

जाहिर है, जब खुमैनी के निधन के बाद भी ईरानी धार्मिक नेता, ब्रिटेन से संबंधों को दरकिनार करके 'फतवे' को बरकरार रखने पर अटल हैं, तो रुश्दी के सामने आजाद होने के लिए सिवा इसके कोई रास्ता नहीं है कि वे अपने उपन्यास को वापस लें। क्योंकि ईरानी फतवे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुश्दी के समर्थन में जो हो-हल्ला हुआ था,.वह भी अब दम तोड़ चुका है तथा रुश्दी पूरी तरह से अकेले अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं।

नेल्सन मंडेला

आसार रिहाई के

दक्षिण अफ्रीका की बोथा सरकार की रंगभेदी नीति का विरोध करने तथा दक्षिण अफ्रीका की आजादी का संघर्ष छेड़ने के जुर्म में पिछले लगभग २५ सालों से कैद में रह रहे महान राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मंडेला के प्रति किसको सहानुभूति नहीं? मंडेला के दीवानों को यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि सितंबर '८९ में नेल्सन मंडेला २५ साल की कैद के बाद बिना शर्त रिहा कर दिये जायेंगे।

असल में खबर यह है कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रवादी दल के नेता एफडब्ल्यूडी क्लर्क, जो शीघ्र राष्ट्रपति पीडब्ल्यू बोथा की कुरसी ग्रहण करने वाले हैं, पर लंदन ने मंडेला की रिहाई के लिए दबाव डाला है तथा क्लर्क लंदन की बात मानने को तैयार हो गये हैं। सवाल उठता है कि आखिर थैचर सरकार मंडेला की रिहाई पर इतना जोर क्यों दे रही है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। ब्रिटेन चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रीटोरिया शासन को उसकी रंगभेदी नीति के कारण जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे उसे निजात मिल जाये। हाल में प्रीटोरिया की कुछ खबरों से यह बात स्पष्ट होती है कि दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी के अभाव में चरमराने की स्थिति में पहुंच गयी है। फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव जिस तरह से घट रहा है, उस हिसाब से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को सुचारु ढंग से चलाना कोई हंसी-खेल नहीं।

थैचर सरकार मंडेला की रिहाई के लिए दबाव इसलिए भी डाल रही है ताकि वह कामनवेल्थ के उन सदस्य देशों के समक्ष यह साबित कर सके कि प्रीटोरिया शासन को रंगभेदी नीति समाप्त करने पर मजबूर करने के लिए उन्होंने 'आर्थिक प्रतिबंध' के जिस हथियार का इस्तेमाल किया वह गलत था। साथ ही, ब्रिटेन सरकार मंडेला की रिहाई कराकर यह नाम भी कमाना चाहती है कि उसने प्रीटोरिया शासन की आड़े वक्त में मदद करके उसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पुनः सम्मान दिलाने में मदद की है। जाहिर है, थैचर सरकार यह सब करके पुनः कामनवेल्थ की लगाम अपने हाथों में लेना चाहती है, क्योंकि फिलहाल दक्षिण अफ्रीकी मुद्दे को लेकर ही कामनवेल्थ के सदस्यों द्वारा उसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

नेल्सन मंडेला

सूत्रों का कहना है कि थैचर सरकार तथा क्लर्क के बीच मंडेला की रिहाई के संबंध में जो बातचीत हुई है, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि क्लर्क मंडेला पर इस बात का जोर नहीं डालेंगे कि वे रिहाई से पूर्व हिंसा छोड़ने का वायदा करें। हालांकि एक खबर में तो यह भी बताया गया है कि क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला ने रिहाई की खबर पाकर खुद यह बयान दिया है कि रिहा होने के बाद उनकी पूरी कोशिश होगी कि वे हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें।

अमरीका

जिम राइट का इस्तीफा

जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ पर भारतीय विपक्ष ने 'चारा घोटाले' को लेकर छींटाकशी की थी, बिलकुल उसी तरह लगभग डेढ़ महीने से अमरीकी प्रतिनिधिसभा (हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के अध्यक्ष जिम राइट को आरोपों के वार सहन करने पड़ रहे थे। हालांकि राइट ने अपने ऊपर लगाये जा रहे आरोपों की कई बार सफाई भी दी, किंतु जब सफाई से काम नहीं चला, तो तंग आकर ३१ मई, १९८९ को प्रतिनिधिसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह भी ऐलान कर दिया कि जून के अंत तक वे कांग्रेस भी छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि जिम राइट अमरीकी प्रतिनिधिसभा के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जिनको आर्थिक घोटालों के आरोप के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रतिनिधिसभा को आखिरी बार संबोधित करते हुए जिम राइट ने कहा, "मैं मानता हूं कि मैंने कुछ मामलों में गलत निर्णय ले लिया होगा या मुझसे गलती हो गयी होगी। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां मैंने अपने नजरिये से फैसला किया जो हमारे साथियों को पसंद नहीं आया। यही मेरा जुर्म है। इसलिए आज मैं वह जिम्मेदारी आप सबके सुपुर्द करता हूं जो आप सब ने मुझ पर विश्वास करके मुझे सौंपी थी। मुझमें अपने साथियों की छींटाकशी सहन करने की अब और शक्ति नहीं। फिर प्रतिनिधिसभा आपसी छींटाकशी की जगह नहीं, अपितु देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने की जगह है। आप जैसे ही नया अध्यक्ष चुन लेंगे मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा।"

असल में प्रतिनिधिसभा में उपस्थित रिपब्लिकन सदस्य जिम राइट से छुटकारा पाने के लिए 'इथिक्स कमेटी' में विचाराधीन आरोपों को आधार बनाकर उन पर व्यंग्य कसते नहीं बाज आ रहे थे। जबकि कमेटी फिलहाल किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पायी थी। बात सिर्फ आरोपों तक ही थी। किंतु विपक्ष को तो बहाना मिलना चाहिए सो हल्ला शुरू हो गया। ८ जून को राइट की अध्यक्षता में अमरीका के वाशिंगटन राज्य के डेमोक्रेट थामस एस फोली को प्रतिनिधिसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। थामस फोली ने अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करने के बाद प्रतिनिधिसभा के सदस्यों से आपसी भेदभाव समाप्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि अमरीका पर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति का वर्चस्व तो है, किंतु ४३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा में डेमोक्रेट पार्टी बहुसंख्यक है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अकसर महत्वपूर्ण मामलों में डेमोक्रेट सदस्य टांग फंसा देते हैं और रिपब्लिकन मनमाफिक नीति बनाने में सफल नहीं हो पाते। यही वजह है कि अमरीकी प्रतिनिधिसभा में भी भारतीय लोकसभा जैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। किंतु इतना जरूर है कि डेमोक्रेट भले सत्ता में नहीं, किंतु जहां राष्ट्रहित होता है, वहां वे दलीय भेद को वरीयता नहीं देते।

—विदेशी डेस्क से, तारिक खान

जिम राइट अमरीकी प्रतिनिधिसभा (हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं, जिनको आर्थिक घोटालों के आरोप के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा।

सुरेंद्र मोहन

६४वां संविधान संशोधन विधेयक

किस जनताराज के लिए ?

राजीव गांधी जब यह कहते हैं कि 'विपक्ष की एक-एक पार्टी ने, एक-एक नेता ने' पंचायत राज संबंधी ६४वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया, तब वे अपने उन भाषणों को जैसे जानबूझ कर भुला देते हैं, जिनमें उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात के पंचायती राज की बार-बार प्रशंसा की है। कर्नाटक में पंचायती राज की वर्तमान-व्यवस्था का सेहरा जनता पार्टी (अब जनता दल) की सरकार के सिर पर बंधा है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम और पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे के सिरों पर। (वामपंथी मोर्चे में दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं और उनके सहयोगी दल क्रांतिकारी समाजवादी दल और फार्वर्ड ब्लाक भी।

चिराग तले अंधेरा : मतलब यह कि राजीव गांधी के पंचायती राज संबंधी विधेयक से पहले ही इन सभी दलों ने ही पंचायती राज व्यवस्था 'वास्तविक' रूप में लागू कर दी थी। जब राजीव को उसकी सफलता के उदाहरण ढूंढने पड़े, तो उनको इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारों का उल्लेख करना पड़ा। उधर, न केवल उन्होंने गुजरात के अतिरिक्त किसी भी कांग्रेसशासित साफ राज्य का उल्लेफ नहीं किया, बल्कि जब वे ६४वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करा रहे थे, उसके कुछ ही पहले महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनावों को विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थगित किया गया और २२ मई को अर्थात् विधेयक पेश करने के एक सप्ताह बाद उड़ीसा में भी पंचायत चुनावों को टाला गया। अब यदि हम यह याद रखें कि ६४वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य आकर्षण यह है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप में हों, तो क्या इंकाशासित इन दो राज्यों में इसकी ही, ऐसे ही समय पर, अवहेलना राजीव गांधी और उनकी पार्टी के इरादों और नेकनीयती पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाती ?

उक्त विधेयक में जहां बहुत ही अच्छी बातें हैं, वहां केंद्रीकरण को बल देनेवाली यह व्यवस्था भी है कि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करायेगा और उनके आय-व्यय के आलेखों की जांच भी केंद्रीय महालेखाधिकारी करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों में ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अत्यधिक बढ़ाया है। राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद-३५६ में प्रदत्त अधिकारों का बराबर दुरुपयोग किया है और राज्यों की वित्तीय स्थितियों को दुर्बल बनाया है। बल्कि, विगत साढ़े चार वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री भी हैं, ने अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को कम-से-कम बीस बार बदला है। अपनी मंत्रिपरिषद को तीस बार से अधिक बदला है और यही रवैया दल के पदाधिकारियों की नियुक्तियों व बरखास्तगियों के बारे में अपनाया है।

जब ऐसी पार्टी और उसका केंद्रीय नेतृत्व अकस्मात् विकेंद्रीकरण का राग अलापने लगे, संसदीय आम चुनाव से सात मास पहले पंचायती राज संबंधी विधेयक प्रस्तुत करे, तो आश्चर्य और संदेह होना स्वाभाविक है। इस विधेयक को १५ मई को संसद में रखा गया, जबकि उससे दस दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उनसे इस पर राय नहीं ली गयी। संसद में विपक्षी दलों से भी कुछ सलाह नहीं की गयी। विधेयक को प्रस्तुत करते समय यह ध्यान भी नहीं दिया गया कि संविधान में केंद्र-राज्यों के अधिकारों का जो निर्धारण किया गया है, उसमें पंचायती राज को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। स्वय सरकार ने संसद के इसी सत्र में अपने द्वारा नियुक्त सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट पेश की, उसकी उन सिफारिशों को भी ठुकरा दिया गया जो इस विषय से संबंध रखती थीं। बल्कि, अब तो यह तथ्य भी सामने आया है कि सरकार द्वारा नियुक्त सिंघवी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १९८७ में ही दे दी थी, उसको भी सरकार ने बराबर छिपाये रखा। आखिर जनता को अधिकार देने के काम में ऐसे एकतरफा, गोपनीय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार की क्या जरूरत आ पड़ी थी ?

बुनियादी सवाल : इन सब तात्कालिक प्रश्नों से कहीं बुनियादी बात यह है कि क्या वर्तमान विधेयक उसी प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिसकी कल्पना गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेताओं ने की थी ? अथवा क्या यह समाजवादी आंदोलन के 'चौखंभा राज' की सोच के अनुरूप है ? गांधीजी ग्राम-स्वराज की बात कहते थे और मानते थे कि सत्ता का प्राथमिक स्रोत गांव पंचायत होगी और उससे ऊपर के जितने स्तर होंगे, उनकी सत्ता उत्तरोत्तर कम होती जायेगी। जयप्रकाश नारायण वास्तविक सत्ता के हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत करते थे, जिसमें अफसरशाही के प्रशासनिक अधिकारों को भी पंचायती राज संस्थाओं के हाथ में देना जरूरी है। वे कहते थे, "या तो जिलाधीश गायब हो जायेगा अथवा जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।" उनकी एक अन्य उक्ति है, "पंचायती राज जितना जल्दी हो सके, अपने अधीन कर्मचारियों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित करे और वे कर्मचारी पंचायती राज के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हों।"

समाजवादी विचारकों का 'चौखंभा राज' केवल पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता हस्तांतरण तक ही सीमित न था, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों और सभी स्तरों पर सत्ता के ऐसे संतुलित वितरण पर बल देता था, जिसमें प्रत्येक स्तर के कर्तव्यों के अनुरूप अधिकार व साधन मिलें।

परंतु, यदि वर्तमान विधेयक का अध्ययन करें, तो इसकी सचाइयां स्पष्ट हो जाती हैं, मसलन :

१. पंचायती राज संस्थाओं को केवल विकास संबंधी अधिकार दिये जा रहे हैं, प्रशासन संबंधी नहीं।

२. जिलाधीश व अन्य अधिकारी इन संस्थाओं के अधीन न होंगे, बल्कि उनका दर्जा लगभग वही रहेगा जो अंग्रेजी राज से अब तक स्वतंत्र भारत में भी चला आ रहा है।

३. राज्य सरकार इन संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकेगी।

४. जैसा कि पहले कहा गया है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और केंद्रीय महालेखाधिकारी इन संस्थाओं के चुनावों एवं आय-व्यय आलेखों की जांच करेंगे।

५. इन संस्थाओं को जो वित्तीय साधन मिलेंगे, उनका निर्धारण प्रतिवर्ष केंद्र सरकार करेगी और वे इस विषय में मुख्यतः उसके अधीन रहेंगे।

इन संक्षिप्त विवरण से ही यह बात साफ हो जाती है कि राजीव गांधी जिस विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं, वह गांधीजी व जेपी की सोच से बहुत दूर और बहुत नाकाफी है। जहां तक 'चौखंभा राज' के संतुलित सत्ता-वितरण की बात है, यहां इतना ही कहना काफी होगा कि ५ मई को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने कहा था कि शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली पंचायतों के बीच शक्तिहीन राज्य हमारी राज्य व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। राज्यों के अधिकारों पर पं० नेहरू स्वयं कितना बल देते थे, वह उनके

१९५४ में १५ नवंबर को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाषण से स्पष्ट होता है, "हम एक संघ राज्य हैं, जिसमें राज्यों की काफी स्वायत्तता है। मैं समझता हूं कि स्वायत्तता अच्छी है और मैं अधिकतम संभव विकेंद्रीकरण में विश्वास करता हूं बशर्ते वह देश की एकता को दुर्बल न बनाये या उसकी प्रगति में बाधक न हो।"

सत्ता हस्तांतरण में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है। स्वय राजीव गांधी ने ५ मई, १९८९ को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा की, "भारत के बड़े भाग में जनता, प्रशासन को अपने प्रतिनिधियों के अनुचर के रूप में नहीं, बल्कि अफसरशाही-तानाशाही के रूप में देखती है।" उन्होंने कहा कि उसको जनता का प्रतिनिधि और उसके प्रति उत्तरदायी बनाना जरूरी है। परंतु, विधेयक में इस तरह का कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं है कि प्रशासन और व्यवस्था नियमन की बात तो छोड़ें, विकास कार्यों में भी जन प्रतिनिधि अफसरशाही के अधीन होंगे अथवा अफसरशाही उनके अधीन होगी।

कर्नाटक में इस सवाल पर बहुत सोच-विचार करके यह व्यवस्था बनायी गयी कि जिला परिषद को एक मुख्य सचिव की सेवा प्राप्त होगी, जो सरकार द्वारा नियुक्त होगा। किंतु वह जिला परिषद के अधीन होगा, जबकि प्रशासनिक सेवा में उसका रुतबा जिलाधीश से अधिक होगा। परंतु, जो अधिकार जिला परिषद के क्षेत्र में नहीं हैं, उनके संबंध में जिलाधीश जिला परिषद से स्वतंत्र होगा, जैसे कि अपने क्षेत्र में जिला परिषद होगी। यह व्यवस्था काफी कारगर है, किंतु प्रधानमंत्री ने स्वयं जिस विधि को अफसरशाहों की तानाशाही कहा, उनके संबंध में भी कर्नाटक के अनुभव से कुछ नहीं सीखा है।

पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और दूसरी ओर, रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने 'जवाहर रोजगार योजना' को उनके सुपुर्द कर दिया है। अभी तक चली आ रही तीन योजनाओं-समन्वित ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना और ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी योजना—को मिलाकर यह योजना चलायी गयी है, जिसके अंतर्गत २१०० करोड़ रुपए केंद्र से सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेंगे। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और केंद्र ने इस में बदलाव किया है कि पहले ऐसी केंद्र-प्रायोजित योजनाएं राज्यों को दी जाती थीं और अब सीधे ग्राम पंचायतों को दी जायेंगी।

जवाहर रोजगार योजना: इस केंद्र प्रायोजित जवाहर रोजगार योजना के अध्ययन से यह आश्चर्य होता है कि इसमें कितना भारी केंद्रीकरण और लचकहीनता है, साथ ही इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में जैसी एकरूपता अव्यावहारिक है, वह भी हैं। योजना के कार्यान्वियन के लिए केंद्र सरकार ने एक मार्गदर्शक नियमावली जारी की है, जिसमें १५ हजार शब्द हैं और वह इतनी विस्तृत है कि वह पंचायतों के फैसले के लिए कुछ बाकी ही नहीं छोड़ती। कहने को तो जनता द्वारा अनुभूत आवश्यकताओं की बात कही गयी है, किंतु केंद्र ने ही उनको चार क्षेत्रों में नामांकित करके यह भी निर्धारित कर दिया है कि वित्तीय साधनों को किस-किस क्षेत्र में किस अनुपात से आवंटित किया जायेगा। न तो स्थानीय विभिन्नताओं को कोई स्थान दिया गया है, न ही अब तक हुए विकास की स्थिति को। जनता की इच्छा पर तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है।

इससे भी अधिक नियमावली का यह प्रावधान है कि जिलास्तरीय संस्थाओं को अधिकार हैं कि वे पंचायतों के लिए वार्षिक कार्य योजना के बाहर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायतें उस कार्य योजना के अंतर्गत भी जो बातें निर्धारित करें, उनकी स्वीकृति भी ब्लाक समिति के अधिकारियों से लेनी होगी।

राजीव गांधी के पंचायती राज संबंधी विधेयक से पहले ही इन सभी दलों ने ही पंचायती राज व्यवस्था 'वास्तविक' रूप में लागू कर दी थी। जब राजीव को उसकी सफलता के उदाहरण ढूंढ़ने पड़े, तो उनको इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारों का उल्लेख करना पड़ा।

परंतु, यह अद्भुत प्रकार के जनता के राज की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वियन तो ग्राम पंचायतें करेंगी, परंतु राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने तीन प्रकार की रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी—१. तार द्वारा मासिक रिपोर्ट, २. एक विस्तृत त्रैमासिक रिपोर्ट और ३. जून के अंत तक वार्षिक रिपोर्ट।

इस विवरण से इन निष्कर्षों को रेखांकित किया जा सकता है:

(क) जवाहर रोजगार योजना का रूप-आकार मूलतः केंद्रीकरण का ही अंग है।

(ख) पंचायतों को पूर्व निर्धारित योजनाओं को ही कार्यान्वित करना पड़ेगा।

(ग) पंचायतें एक जटिल नियमावली की जकड़ में लायी जा रही हैं।

(घ) इससे लालफीताशाही में कमी नहीं, बढ़ोतरी ही दिखायी दे रही है।

(ङ.) पंचायतें अफसरशाही और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेंगी और उनका स्वयं का फैसला करने का अधिकार बहुत ही कम है।

(च) योजना में किसी लचक, संशोधन की संभावना, स्थानीय जनता की इच्छा आदि का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

केंद्र का जाल: यह पंचायतों को सत्ता-हस्तातंरण और जनता को अधिकार देने का तरीका न होकर उनको केंद्रीकरण और अफसरशाही के जाल में फांस लेने का ही तरीका हो सकता है। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि यह उन महान नेता के नाम पर किया जा रहा है जो अधिकतम संभव विकेंद्रीकरण के हिमायती थे।

राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर सकती हैं। इस संदर्भ में, स्पष्ट शर्तों और परिस्थितियों का उल्लेख करना जरूरी था। यह भी प्रावधान करना था कि राज्य सरकार जब भी ऐसा कार्य करेगी, तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगी। केंद्र ने जिस निर्लज्जता के साथ ३५६वें अनुच्छेद का दुरुपयोग किया है और राज्य सरकारों व विधानसभाओं को भंग या निलंबित किया है, उसको ध्यान में रखकर यह व्यवस्था जरूरी थी कि वैसा पंचायती राज संस्थाओं के साथ न हो। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव कराने में केंद्र में शासक दल के इच्छानुसार कार्य करके बार-बार टालमटोल किया है, वैसा ही भंग की गयी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के संबंध में भी हो सकता है। इस विधेयक की बड़ी बुनियादी कमियों में इन बातों को भी गिनना चाहिए।

विधेयक में यह भी कमी है कि वह जिला परिषद और ग्राम पंचायत के ढांचे के संबंध में राज्यों को अपने-अपने तौर पर फैसला करने का अवसर नहीं देता, जैसा कि अशोक मेहता समिति से सुझाया था। वहां उसका यह गुण है कि उसने दुर्बलतर समुदायों एवं महिलाओं के लिए चुनावों में आरक्षण का प्रावधान किया है। यह स्वागतयोग्य है। अलबत्ता यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आंध्रं प्रदेश और कर्नाटक में न केवल सदस्यों के चुनाव में इन समुदायों को आरक्षण दिया गया है, बल्कि पदाधिकारियों के चुनाव में भी। यह कहना जरूरी नहीं है कि निचले स्तरों पर चुनिंदा पदाधिकारियों का (उनमें आरक्षण का) अत्यधिक महत्व होता है। ■

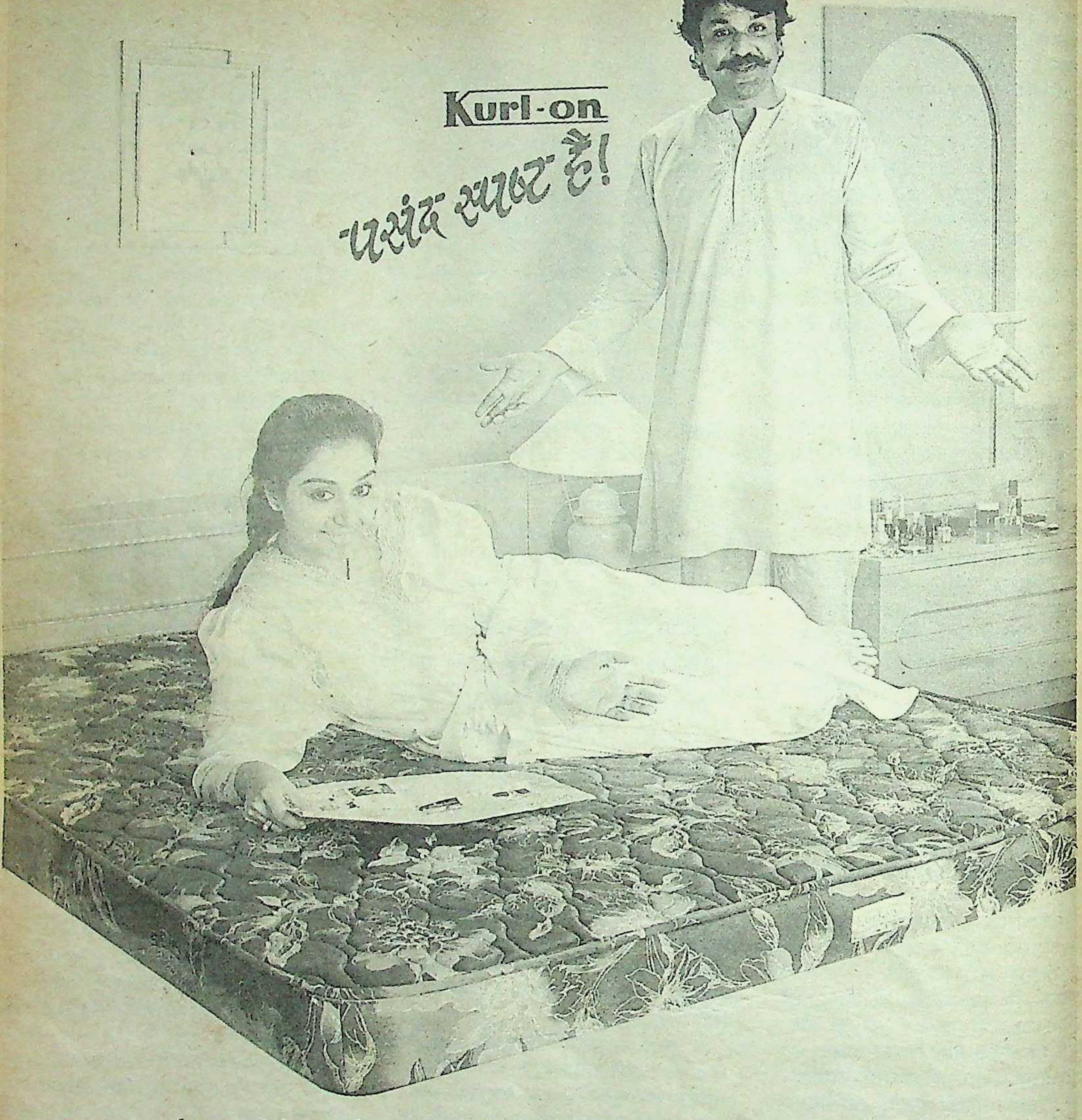

शुभ रात्रि शुरू होती है कर्ल-ऑन गद्दों के साथ।
आराम, सहारे और शान का उत्कृष्ट संगम। हरदम।
आपको भरपूर, आरामदेह नींद देने के लिए।
सालों-साल चलने के लिए।

आराम. सहारे. शान के लिए।
Kurl-on®
भारत में सबसे अधिक बिकने वाले गद्दे।

MASS: KCPL/89

Karnataka Consumer Products Ltd.
Marketing Division: Industry House, 45 Fair Field Road, Bangalore 560 001. Phone: 70769/72710.
Area Sales Offices & Showrooms: 1764 Partap Street, Chuna Mandi, Pahar Ganj, **NEW DELHI** 110 055. Ph: 732133, 772019; 26 Mangal
Sadan, Anekant Nagar, Near Lily Talkies, Jahangirabad, **BHOPAL** 462 008. Ph: 67874; 109/375 R.K. Nagar, G.T. Road, **KANPUR** 208 012.
Ph: 243965(PP); 88, New Textile Market, Panderi, **RAIPUR**; C-23 Satyam Shopping Centre, M.G. Road, Ghatkopar (E), **BOMBAY** 400 077
Ph: 5113220; Road No. 6A, Dayal Mansion, Rajendra Nagar, **PATNA** 800 016. Ph: 57911.

बहुपत्नी प्रथा

धर्म के परदे में

कोई हिंदू, ईसाई या पारसी एक साथ दो पत्नियां नहीं रख सकता, लेकिन मुस्लिम पर्सनल कानून इसकी इजाजत देता है। इसका नाजायज फायदा उठाकर गैरमुस्लिम शादीशुदा मर्द दूसरी महिला से अपने अवैध संबंधों को ढकने के लिए इस्लाम कबूल करके उससे शादी कर लेता है और पहली पत्नी नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन भारतीय कानून उस मर्द को कोई सजा नहीं दे सकता। सबको बराबरी का दर्जा देनेवाला भारतीय संविधान धर्म की ओट में महिलाओं के साथ हो रहे इस पक्षपात पर मौन क्यों है?

Goutam Chakravarti

बस में यात्रा करते समय किशोरी मीना की मुलाकात जीतेंद्र माथुर से हुई। बातों-बातों में निकटता हो गयी। फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों पहले दोस्त बने और फिर एक दूसरे के प्रेम दीवाने। जोड़ी बहुत अच्छी थी। प्रेम के बाद शादी हुई, बच्चे हुए, सुखी पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। अचानक एक दिन तड़के मीना को पता चला कि माथुर साहब मुसलमान बन गये हैं और उन्होंने सुनीता नरूला नामक लड़की से शादी रचा ली है। दोनों अपने नाम बदल कर अब्दुल्ला और फातिमा खां बन गये हैं। अबला पर क्या बीती, वही जानती है। रोती हुई मीना बताती है, "हम (वह और उसके बच्चे) मुर्दों का जीवन जी रहे हैं।"

२४ वर्षीया खूबसूरत होटल अधिकारी रेणू ने दीपक राविसन से तीन साल प्रेम-संबंध चलने के बाद शादी कर ली। इस जोड़े के जीवन में कोई कमी नहीं थी—न धन की, न आपसी रिश्ते की गर्माहट की, न प्रेम की। सहसा एक दिन रेणू के पतिदेव कामाक्षी नामक महिला के साथ चल दिये। कामाक्षी उनकी दूसरी वैध पत्नी थी, क्योंकि दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस घटना से रेणू को इतना जबरदस्त सदमा लगा कि उससे वह अभी तक उबर नहीं सकी।

२६ वर्षीया रत्ना और ३० वर्षीय मारी मुत्ता परंपरावादी दक्षिण भारतीय परिवारों के थे। मारी मुत्ता दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी करता था, जबकि रत्ना आदर्श गृहिणी की तरह अपने पति और तीन छोटे बच्चों की प्रत्येक सुख-सुविधा का खयाल रखती थी। रत्ना से जब किसी ने मुत्ता के अवैध संबंधों की चर्चा की थी, तब उसे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन उसे बाहर करके मारी मुत्ता अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। शादी करने के लिए इस जोड़े ने भी गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उस असहाय हिंदू पत्नी को बाहर फेंक दिया गया।

'पर्सनल ला' की आड़: सुनीता लंबी, गोरी और पढ़ी-लिखी युवती है, किसी भी वैवाहिक विज्ञापन में बहू की 'मांग' में फिट बैठनेवाली। वह अपने पति विलायत राज से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन यह युवा दम्पती अपना घर ठीक से बसा पायें, इसके पहले ही विलायत राज ने अपने को विलायत खां घोषित कर दिया। फिर उन्हें मेहरजहां से दूसरी शादी करने का पासपोर्ट मिल गया। अन्य भारतीय महिलाओं की तरह भाग्यवादी सुनीता भी भगवान और उसके न्याय के भरोसे बैठी है। भगवान उसकी रक्षा करें। लेकिन क्या अल्लाह भी उसकी पुकार सुनेगा?

यह अभिशाप भुगतनेवाली यही चार महिलाएं नहीं हैं। उर्मिला, रजनी, पूजा, कविता, श्रीमाला, इन सबके साथ भी यही नाटक दोहराया गया है। सिर्फ पात्र बदलते रहे हैं। ये किस्से सिर्फ दिल्ली के ही नहीं हैं, देश के सभी महानगरों से इसी तरह की कथाएं सामने आ रही हैं। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि दूसरी शादी के लिए हिंदू से मुसलमान (जिनका पर्सनल ला दूसरी शादी की इजाजत देता है) बननेवाले अच्छे घरों के और पढ़े-लिखे लोग ही हैं। प्रसिद्ध समाजसेविका सरला मुद्गल बताती हैं, "इससे भी दिलचस्प बात यह है कि धर्म बदलनेवालों को दुश्चरित्र नहीं कहा जा सकता।" एक शादीशुदा मर्द दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने की जगह अपना धर्म बदल कर इस महिला को दूसरी पत्नी होने का सामाजिक प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। इस पूरे प्रकरण में तीन बुनियादी मानवीय संवेदनाओं—प्रेम, कामवासना और भावावेश—के अलावा 'पर्सनल ला' की भी बड़ी भूमिका होती है।

मुस्लिम विवाह विलयन कानून, १९३९ के चौथे खंड में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी दूसरे धर्म को अपना लेने के बाद शादी का पहला रिश्ता स्वतः समाप्त हो जायेगा। दूसरी ओर, पारसी विवाह और तलाक कानून के चौथे खंड में कहा गया है कि पति के धर्म-परिवर्तन के बाद पुराना वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं होगा और वह कानूनी रूप से दूसरी शादी करने का हकदार नहीं होगा। अगर वह दूसरी शादी करता है, तो उसे एक से अधिक पत्नियां रखने का अपराधी माना जायेगा। इसके विपरीत धर्म-परिवर्तन के बाद शादीवाले मुद्दे पर हिंदू और ईसाई पर्सनल ला में एकदम चुप्पी साधी गयी है। ऐसा करके इन कानूनों ने अपने दायरे में आनेवाले पुरुषों को इस्लाम कबूल कर एक से अधिक शादी करने की पूरी छूट दे दी है। अपने धर्म को मानते हुए ये लोग ऐसा नहीं कर सकते।

संविधान का उल्लंघन: जीतेंद्र माथुर उर्फ अब्दुल्ला खां की दूसरी पत्नी सुनीता नरूला उर्फ फातिमा खां से इस संदर्भ में पूछने पर फटाका जवाब मिलता है, "राजीव गांधी के पास जाइये और इस कानून को बदलने को कहिए, जिससे कोई मुसलमान दूसरी शादी न कर सके।" दरअसल, सरकारी मशीनरी—पुलिस और अदालतों—के सजग और सक्रिय न रहने के कारण ही इस तरह का सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। मूल रूप से हिंदू और मुस्लिम पर्सनल ला पुरानी परंपराओं के आधार पर ही बने हैं। पहले हिंदू लोग हिंदू कानून और मुसलमान इस्लामी कानून से शासित होते थे और सरकार इस मामले में दखल नहीं देती थी। इसलिए संविधान में सबको बराबरी देनेवाले कानून के बावजूद तरह-

मूल्य ६.००

पावस विशेषांक

- **- बेला का बलिदान** (मर्मस्पर्शी ऐतिहासिक कथा)
- **-आत्मदण्ड** (अन्तरात्मा पर अपराध के बोझ की घुटन से आत्महत्या करनेवाले सम्पन्न व्यक्ति की अन्वेषण-परक अपराध-कथा)
- **-पाषाण-हृदय** ऐसे मां-बाप की कहानी जिनका हृदय प्रेम-विवाह करने वाली पुत्री की मांग का सिन्दूर घुल जाने पर भी न पिघला)
- **-टकराव का अभिशाप** (अन्ध विश्वासों से जुड़ी परम्परा को तोड़ने के प्रयास में स्वयं टूट जाने वाले मोघिया नवयुवक की व्यथा-कथा)
- **-एक पुत्र के लिए** (पुत्र प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षा को तृप्त करने के लिए अपराध की ओर मुड़ने वाली नारी की कहानी)
- **-सहारनपुर का प्रभात-कांड** (अन्वेषण परक अपराध कथा)
- **-खुदा का इंसाफ** (जिन्दगी की झोली में कांटे भरने वाली एक ऐसी नारी की कहानी, जिसके शूल जब देवी कृपा से फूल बनने लगे, तब संसार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा)

मनोहर कहानियाँ

अतिरिक्तांक

अगस्त '८९ में प्रकाश्य

तरह के पर्सनल ला आज भी बरकरार हैं।

१९३७ में शरीयत कानून लागू होने के बाद स्थिति बदली। यह कानून इसीलिए बना, क्योंकि जो अनगिनत हिंदू धर्म बदलकर मुसलमान बन गये थे, वे भी हिंदू परंपराओं से बंधे हुए थे, उन्हीं नियमों से संचालित होते थे। मुस्लिम जनमत को यह नापसंद था। इस कानून के बन जाने से सरकार हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ गयी। लेकिन अब सरकारी हस्तक्षेप मुसलमान, ईसाई और हिंदू पत्नियों के बीच में भेदभाव करनेवाला भी हो गया। चूंकि यह संविधान की धारा १५ (१) का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए कायदे से इसके लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल ला को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। प्रसिद्ध महिला वकील पद्मा जैन बताती हैं, "मुस्लिम कानून में बहुपतित्व की इजाजत इसी शर्त के साथ दी गयी है कि मर्द पहली और दूसरी पत्नियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आज यही भेदभाव करने के लिए ही हिंदू और ईसाई मर्द इस कानून की शरण ले रहे हैं। धर्मांतरण करनेवालों का यह कतई मंशा नहीं है कि वे पहली और दूसरी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। इसलिए दूसरी शादी सामान्य है ही नहीं।" पद्मा जैन बताती हैं कि दूसरी शादी को संविधान की धारा २५ (१) के आधार पर जो अंत:करण के आधार पर फैसले लेने की आजादी देता है, सही नहीं ठहराया जा सकता।

पत्नी की लाचारी: मुस्लिम पर्सनल ला भले ही बहुपत्नीत्व की इजाजत देता हो, लेकिन बहुपत्नीत्व में विश्वास रखनेवाले इस्लाम में भी विश्वास रखते हों, यह संदेहास्पद है। जहां तक धर्माचरण की बात है, संविधान की धारा २५ (२) लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, भले ही वह धार्मिक मान्यता के अनुसार शादी करने की बात क्यों न हो। यही कारण है कि इस्लाम को छुए बिना भी १९३९ के मुस्लिम विवाह विलयन कानून को लागू किया जा सकता है। वकील मोहिंदर मल्होत्रा इस पूरी स्थिति को इन शब्दों में बताते हैं, "यह कानून हमारे दबे लोगों के खिलाफ है। अलग-अलग धर्मों के पर्सनल ला बहुत स्पष्ट नहीं हैं और इनसे अस्तव्यस्तता फैलती है।"

कानून में गड़बड़ी होने के बावजूद हाईकोर्ट के तीन वकीलों—मोहिंदर मल्होत्रा, पद्मा खन्ना और उर्मिला कपूर—ने मीना माथुर, रत्ना मुत्ता और सुनीता जुनेजा की ओर से याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें एक से अधिक शादी करने (४९८-एं), प्रताड़ना (४९४-ए), दहेज और शारीरिक यातना देने के आरोप लगाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि हाल में इन्हीं वकीलों ने राजेंद्र कुमार और उनकी पहली पत्नी विजया का पुनर्मेल कराने में सफलता प्राप्त की है। राजेंद्र कुमार ने कुछ समय के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। सामाजिक कार्यकर्ता यशवंत कहते हैं, "अधिकांश मामलों में पहली पत्नी या तो खामोश रह जाती है या कानूनी लड़ाई से हाथ खींच लेती है। हिंदू विवाह कानून की धारा ५-ए के तहत जब तक दूसरी पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती, तब तक पहली पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती। और स्वाभाविक है कि दूसरी पत्नी कोई शिकायत नहीं करेगी।"

इस विषम स्थिति से निबटने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं—निजी कानूनों को स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करना, जिसका एकपत्नीत्व ही बुनियादी उसूल हो; पहली पत्नी को कानूनी कार्रवाई करने की अनिवार्य अनुमति और पूरे भारत के लिए एक समान विवाह और परिवार कानून का निर्माण जो समस्त धर्मावलंबियों पर लाजिमी तौर से लागू हो। अभी तक इस मसले पर अदालतों का रुख बहुत स्पष्ट नहीं रहा है और वे जैसे-तैसे इसे टालती रही हैं। अब यही आशा की जा सकती है कि जनचेतना बढ़ने के साथ कानूनी और सरकारी मशीनरी इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए अधिक कारगर रवैया अपनायेगी। श्रीमती मुद्गल कहती हैं, "लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि कैसे पढ़ी-लिखी, नौकरीपेशा महिलाएं भी सामाजिक कलंक के भय से प्रतिरोध या शिकायत करने के लिए आगे नहीं आतीं।"

—राजन गुहा

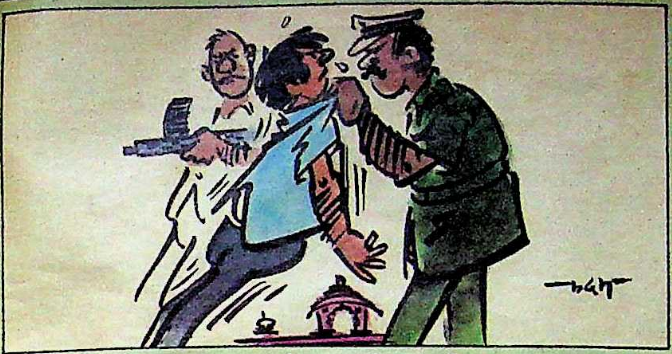

जयपुर की मुस्तैद पुलिस

हमारी पुलिस चोर-डाकुओं, लफंगों-लंपटों और उग्रवादियों को पकड़ने में चाहे भले कम नामवरी हासिल करे, लेकिन बेगुनाह लोगों को पकड़कर उन्हें असामाजिक तत्व घोषित करने में वह अपना कोई सानी नहीं रखती। आये दिन सरे आम शरीफ और सीधे-सादे लोगों की तलाशी शुरू हो जाती है और बेचारे कितने ही थानों और चौकियों तक की यात्रा के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले दिनों जयपुर की पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया—हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ० देवीलाल के पोते को पकड़कर।

हुआ यह कि जयपुर में एक विवाह में शिरकत करने आये देवीलाल के पोते चंद्र सिंह जब जयपुर के दर्शनीय स्थलों के अवलोकन के लिए स्टेनगनधारी अंगरक्षकों से लैस होकर बाहर निकले, तो जयपुर पुलिस के कान खड़े हो गये। पुलिस को लगा यह कोई आतंकवादी दस्ता है। चंद्र सिंह का नाहरगढ़ किले में प्रवेश करना ही था कि पुलिस ने घेरेबंदी कर उन्हें धर दबोचा और ब्रह्मपुरी थाने में ला बिठाया। जब पुलिस को पूछताछ के दौरान असलियत का पता चला, तो पुलिस के पसीने छूट गये। पुलिस ने तुरंत क्षमायाचना की और उन्हें ससम्मान विदा किया।

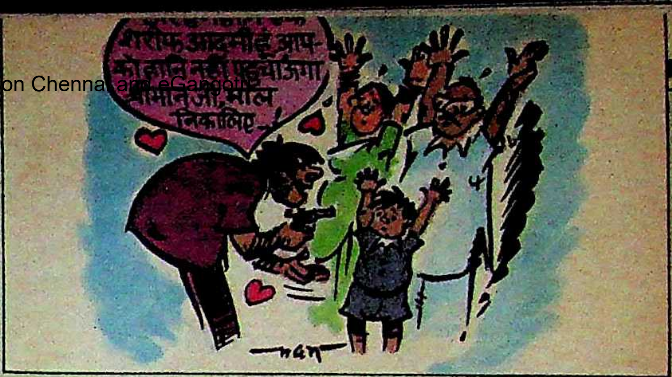
शरीफ आदमी हूं आप-को हानि नहीं पहुंचाऊंगा श्रीमान जी, माल निकालिए

नेक लुटेरा

लुटेरे तो चेहरे-मोहरे से ऐसे खूंख्वार होते हैं कि देखनेवालों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा लुटेरा हो जो हाथ में कट्टा और छुरा तो लिये हो, लेकिन डराने-धमकाने की जगह लुटनेवाले के भले-बुरे का ख्याल रख प्रेम से लूटपाट करता हो, तो फिर बात ही क्या! पिछले दिनों तमिलनाडु पुलिस की अपराधशाखा ने बंबई में अंतर-राज्यीय स्तर के एक ऐसे ही कुख्यात लुटेरे को पकड़ा है। वह नेक लुटेरा है। २१ वर्षीय बेबी उर्फ वर्गीज कालीकट के पास कक्कायम का रहनेवाला है। वह किसी भी धनिक के घर में हाथ में कट्टा या छुरा लिये घुस जाता है और बड़ी ही मासूमियत के साथ मकान मालिक से कहता है कि आप डरिये नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं। बस आपके यहां जो भी बहुमूल्य चीजें हैं, सब निकाल दीजिए। सारी चीजों के निकल जाने पर वह मकान मालिक से यह भी अनुरोध करता है कि इन चीजों में किसी चीज से घर के किसी सदस्य का यदि आत्मीय लगाव है, तो वह चीज वह छोड़ सकता है। इस प्रकार बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वह सारी चीजों को उठाकर नौ दो ग्यारह होता है। हाल ही वह कट्टे की नोक पर एक टेक्सटाइल विशेषज्ञ के घर से बातों-बातों में तकरीबन एक लाख के कीमती गहने उड़ाने में सफल रहा। अंततः बंबई में वह धर दबोचा गया। पुलिस ने उसके पास से लगभग ८ लाख का सामान बरामद किया। बाद में पता चला कि लूटपाट की तकरीबन अट्ठारह घटनाओं में पुलिस को उसकी खोज थी।

जेबकतरों की नयी भाषा

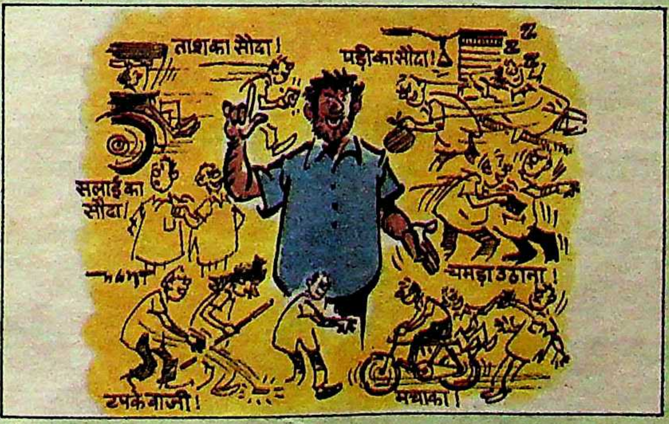
ताश का सौदा!
पड़ी का सौदा!
सलाई का सौदा!
चमड़ा उठाना!
टपकेबाजी!
मचाका!

जैसे हमारा देश २१वीं सदी में छलांग लगाने के लिए तकनीकी दृष्टि से खूब उन्नति कर रहा है, वैसे ही हमारे देश के जेबकतरे अपनी कला का बड़ी तेजी से उन्नयन कर रहे हैं। अभी तक तो समझा जाता रहा है कि इशारे या संकेत से केवल स्काउट या ट्रेन ड्राइवर ही काम करते हैं, लेकिन हमारे देश के जेबकतरों ने भी सांकेतिक भाषा ईजाद कर रखी है।

बेचारा राहगीर क्या जाने कि 'मचाका' क्या होता है? इस शैली में दो जेबकतरे साइकिल से राहगीर का पीछा करते हैं और उसके पास रुककर धीरे से उसके कंधे पर हलकी टक्कर मारते हैं, उनमें से दूसरा जेबकतरा राहगीर का ध्यान भंग होते ही उसकी जेब पर हाथ साफ कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता और दोनों साइकिल पर सवार होकर भीड़ में गुम हो जाते हैं।

'ताश का सौदा' तकनीक में जेबकतरे अकसर व्यापारियों की जेब पर हाथ साफ करते हैं। जेबकतरे बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से ही व्यापारियों के पीछे लग जाते हैं। वाहन में चढ़ते या उतरते समय धक्कामुक्की की स्थिति पैदा कर अपने शिकार के पास बैठकर उंगलियों में ब्लेड फंसाकर उनकी जेब काट लेते हैं। व्यापारी को पता चले, इसके पहले ही रास्ते में उतरकर वे फरार हो जाते हैं।

'पड़ी का सौदा' तकनीक सोये हुए यात्रियों पर लागू होती है। रेल में सफर के दौरान सोये हुए लोगों के आसपास बैठकर पहले जेबकतरे यह मालूम करते हैं कि यात्री की किस जेब में पैसा है। फिर जहां उसने जंभाई ली कि उसकी जेब साफ कर दूसरे डिब्बे में खिसक लेते हैं।

'चमड़ा उठाना' से मतलब पर्स मारने से है। 'सलाई का सौदा' तकनीक में दो उंगलियों से कमीज की ऊपरवाली जेब से पैसा उड़ाते हैं। 'टपकेबाजी' में जेब तो नहीं काटी जाती, लेकिन सीधे-सादे ग्रामीणों को झांसा दिया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत जेबकतरे किसी भोले-भाले ग्रामीण के आगे-पीछे चलते हैं। पीछेवाला नकली सोने का एक टुकड़ा ग्रामीण के आगे फेंक देता है, पीछे चलनेवाला उसे इस नफासत से उठाता है कि वह ग्रामीण प्रभावित हो जाये। जेबकतरा उस ग्रामीण को सोना मिलने की बात बताता है। स्वभावतः वह ग्रामीण आकर्षित होता है। जेबकतरे ग्रामीण को फंसता देख प्रस्ताव रखते हैं कि यदि वह चाहे तो अपनी अंगूठी या सोने की जंजीर या घड़ी देकर यह सोने का टुकड़ा ले सकता है। जो फंस गया, समझिए वह गया काम से!

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

हमदर्दी से जन्मी लोकप्रियता: एक जनसभा में सरकार पर बरसते हुए आरिफ मुहम्मद खां

बहराइच अग्निकांड

आरिफ का राहत अभियान

आग की भेंट चढ़े बहराइच के ४५१ गांवों के ४१०४ परिवार बेघर-बार हो गये हैं। सरकार ने तो रस्मी राहत पहुंचाकर छुट्टी पा ली, लेकिन वहां के सांसद आरिफ मुहम्मद खां ने राहत का जो अभियान छेड़ा, उससे ग्रामीणों के दिल में उनके लिए स्थायी स्थान बन गया है। अग्निकांड और आरिफ के राहत अभियान की रपट:

यदि किसी क्षेत्र को तहस-नहस कर डालनेवाला कोई बड़ा हादसा हो जाये, सरकार तथा प्रशासन घड़ियाली आंसू दिखाकर बैठ जायें, तो क्षेत्र का हमदर्द सांसद अपना फर्ज निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है और जनहित में कितना कुछ कर सकता है, इसकी एक पुरजोर मिसाल पेश की है जनता दल के महासचिव आरिफ मुहम्मद खां ने। अग्निकांडों से तबाह साढ़े चार सौ गांवों को 'सूम सरकार' से पर्याप्त राहत दिलाने में आरिफ ने अपने अथक परिश्रम और व्यापक अभियान की बदौलत जो कमाल की कामयाबी हासिल की, उसने एक ओर आरिफ को अगले आम चुनाव के लिए बहराइच का सबसे बड़ा नेता बना दिया, तो दूसरी ओर ग्रामीणों की किस्मत में लगी आग को कांग्रेस-इ की किस्मत की ओर मोड़ दिया है।

तबाही का मंजर: बहराइच, आरिफ मुहम्मद का संसदीय क्षेत्र है। कानपुर के बाद अपना चुनाव क्षेत्र बदल कर वे १९८४ में यहीं से इंका उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और जीते थे। हर साल की गरमी इस क्षेत्र पर अग्निकांडों का कहर बरपा करती है। सैकड़ों गांव राख हो जाते हैं और सरकार दिखावे के लिए राहत का ऐलान कर सो जाती है। इस बार मई के पहले हफ्ते तक ४५१ गांव पूरी तरह इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके थे। ४१०४ परिवार इस कदर बेहाल हो गये कि उनके पास तन ढंकने के वस्त्र तक नहीं बचे। १२ ग्रामीण और लगभग २०० पशु आग में स्वाहा हो गये। जिलाधिकारी राजाराम ने तपते तवे पर पानी के छींटे की तरह दैवी आपदा कोष से पांच लाख रुपए इन अग्निपीड़ितों में बंटवाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। इसी बीच ८ मई को आरिफ मुहम्मद खां बहराइच पहुंचे। गये तो वे आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में थे, लेकिन क्षेत्र में हुए अग्निकाडों और इंका सरकार के सौतेले सलूक की जानकारी पाकर अपने फर्ज के प्रति सजग हो गये। उन्होंने नेपाल से लगे क्षेत्र के सीमांत और तराईवाले जंगलों में बसे गांवों में जाकर अपने मतदाताओं की तबाही का मंजर देखा। बेघर हो तपती दोपहरी में पेड़ों के नीचे पनाह ढूंढ़नेवाले गरीब असहाय ग्रामीणों को जीने लायक राहत दिलाने की सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा की और अपने पास की जमा पूंजी से तत्काल राहत की मुहिम शुरू कर दी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को तार भेजकर आरिफ ने अग्निपीड़ितों को राहत मुहैया कराने का अनुरोध किया। इस बीच कई बार दिल्ली जाकर समाजसेवी संस्थाओं, इष्ट मित्रों तथा दयावान धनवानों से कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाकर उन्होंने विपत्ति से जूझ रहे लोगों में अपने स्तर पर लगभग १० हजार धोतियां (जनानी-मर्दानी) तथा अन्य खाद्य सामग्री वितरित कीं। आरिफ बताते हैं, "हरियाणा सरकार ने बहराइच के अग्निपीड़ितों के लिए तीन लाख रुपए की सहायता भेजी, पर उत्तर प्रदेश की सूम सरकार ने तब तक फूटी कौड़ी तक

नहीं दी थी।"

आरिफ का अभियान: केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चुप्पी साध ली जाने पर आरिफ ने इन अग्निपीड़ितों की वेदना को राष्ट्रीय स्तर पर महसूस कराने का इरादा बना लिया। १८ मई को वे अपनी पत्नी श्रीमती रेशमा के साथ पुन: बहराइच पहुंचे। दोनों अलग-अलग दौरे पर निकले। इस बार वे अपने साथ दिल्ली की एक वीडियो कंपनी के कारकुनों को लाये और आग में भस्म हुए गांव तथा त्रासदी से पीड़ित ग्रामीणों पर एक वृत्तचित्र बनवाया। २३ मई को दिल्ली में उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में इस वीडियो फिल्म की मार्फत अग्निकांडों से तबाह ग्रामीणों और नेस्तनाबूद हो चुके उनके घरों की दर्दनाक तस्वीर पेश की। पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने सरकार की उपेक्षा के प्रति ३० मई से बहराइच में अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा की। इस तरह आरिफ ने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति न केवल सरकार के सौतेले व्यवहार को उजागर किया वरन तराई में बसे उस उपेक्षित जिले में हर वर्ष होनेवाले अग्निकांड की विभीषिका का पहली दफा राष्ट्रीय स्तर पर अहसास करा दिया। इसी के बाद उनके संसदीय क्षेत्र में पोस्टर चस्पा कर सूचना दी गयी कि ३० मई को घंटाघर पर जनसभा के बाद कचहरी में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आरिफ अनशन शुरू करेंगे।

अनशन की चेतावनी के बाद प्रदेश सरकार चौकन्नी हुई। सरकारी स्तर पर आरिफ को आश्वस्त किया गया, "पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं, अत: आप उपवास का कार्यक्रम रद्द कर दें।" आरिफ मौखिक आश्वासनों से डिगे नहीं, २८ मई को अपने तय इरादे से सपत्नीक बहराइच पहुंच गये। २९ मई की रात जिलाधिकारी राजाराम ने उनसे अनशन न करने का अनुरोध किया तथा राहत कार्यों की शुरुआत हो जाने की जानकारी दी (वैसे आरिफ को यह जानकारी पहले ही मिल चुकी थी)। ३० मई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने घंटाघर पर विशाल जनसभा की। उसके बाद भारी भीड़ के जुलूस सहित वे कचहरी आये। वहां उनके उपवास स्थल पर आकर जिलाधिकारी ने सरकारी राहत के बारे में उन्हें लिखित जानकारी दी और बताया कि प्रदेश सरकार ने इन अग्निपीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए २५ लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें २० लाख रुपए इस मद में वितरित किये जा चुके हैं। इसी के बाद आरिफ ने अनशन न करने की घोषणा की। बाद में खबर आयी कि प्रधानमंत्री ने भी अग्निपीड़ितों की सहायता के लिए ९ लाख रुपए भेजे हैं।

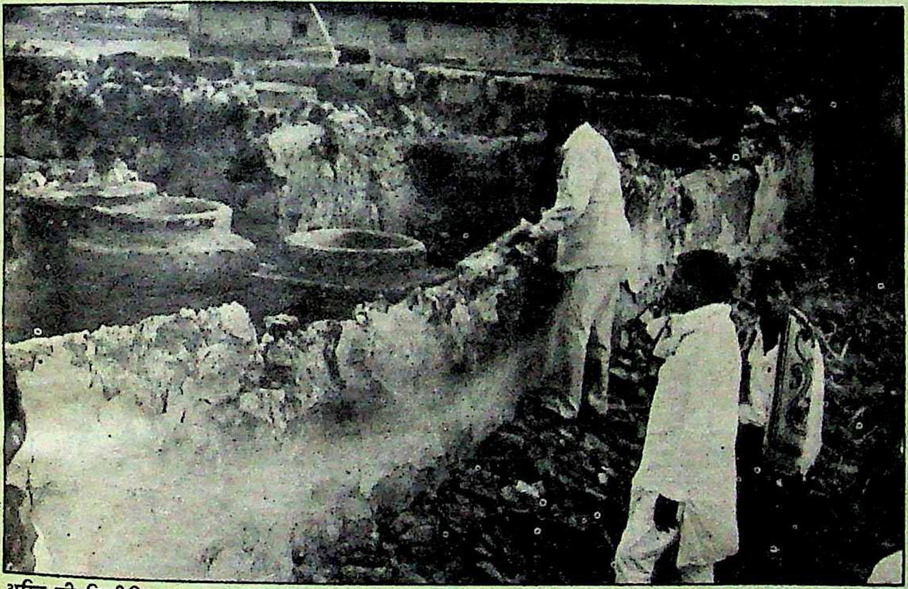

अग्नि की विभीषिका

हाथोहाथ राहत

राजनीतिक पहलू: अग्निपीड़ितों के हक में मानवीय दृष्टिकोण से आरिफ द्वारा छेड़ा गया जिहाद राजनीतिक दृष्टि से भी काफी कारगर रहा। इंका से नाता तोड़ने के बाद भी बहराइच में उनकी पकड़ बरकरार रही है। इस अभियान की सफलता ने इस संसदीय क्षेत्र में उनकी पकड़ और मजबूत कर दी है। दो संसदीय क्षेत्रोंवाले बहराइच जिले में दूसरे सांसद राणावीर सिंह हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी रह चुके सिंह वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। इस चुनावी वर्ष में आरिफ मुहम्मद के बढ़ते प्रभाव के बावजूद सिंह की गतिविधि अपने हितसाधन तक ही सीमित है।

वर्ष १९८५ में जिले की ८ विधानसभाई सीटों में से ६ इंका ने जीती थी। एक सीट निर्दलीय खुर्शीद अहमद (भिनगा) को मिली थी, जो अब इंका में शामिल हो गये हैं तथा दूसरी सीट (फखरपुर) सांसद राणावीर सिंह के निकटतम रिश्तेदार मयंकर सिंह (भाजपा) ने हासिल की थी। आरिफ के इंका से नाता तोड़ने के बाद जिले की इंकाई राजनीति पर भी असर पड़ा और जिले के तीन इंका विधायक देवतादीन, त्रिभुवन प्रसाद चक्रवर्ती और मनहरन नाथ कौल खुले रूप से आरिफ के बगलगीर हो गये हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में भी राणावीर सिंह को आरिफ के आगे मुंह-की खानी पड़ी। नगरपालिका, जिला परिषद और कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पदों पर आरिफ समर्थकों ने विजय दर्ज की। जिले के १९ ब्लाक प्रमुखों में १४ आरिफ के समर्थक हैं। इनमें ४ राणावीर सिंह के संसदीय क्षेत्र के हैं।

अब जद प्रत्याशी के रूप में आरिफ का बहराइच से चुनाव लड़ना और जीतना तय हो गया है। इसी वर्ष होनेवाले चुनाव में दूसरी इंकाई संसदीय सीट भी विपक्ष द्वारा हथिया ली जाने की पूरी संभावना है। जनता दल, खासकर आरिफ, जिले की केसरगंज संसदीय सीट से विपक्ष का कोई धुरंधर संयुक्त प्रत्याशी तलाश करने में लगे हुए हैं। राहत कार्य में सरकार की उपेक्षा और लेटलतीफी ने आरिफ के मकसद को पूरा कर दिया है।

—सुरेश द्विवेदी

छाया: रवींद्र कुमार

उड़िया फिल्मों का पतन

एक जमाने में उड़िया फिल्में उड़ीसा की संस्कृति की छाया हुआ करती थीं। क्षेत्रीय फिल्मों की जिम्मेदारी भी यही होनी चाहिए कि वे अपने समाज की तल्ख सचाइयों का सार्थक स्वर बनें और राष्ट्रीय फलक पर अपनी सांस्कृतिक मर्यादा को स्थापित करें। साधनहीनता की स्थिति से जूझती देश की सभी क्षेत्रीय फिल्मों की हिंदी फिल्मों से ज्यादा जिम्मेदारी इसी मायने में बनती है, फिर उड़ीसा सरकार ने तो फिल्म को उद्योग का दर्जा भी दे रखा है। तब ऐसी कौन सी वजहें हैं कि उड़िया फिल्में दिनोदिन पतन की ओर बढ़ रही हैं। उड़िया फिल्मों का अंतरंग जायजा :

फिल्म 'चका आंखि सबु देखुची' के एक मोहक दृश्य में बायें से गोपा विश्वास, सुजाता आनंद और विजय मोहंती

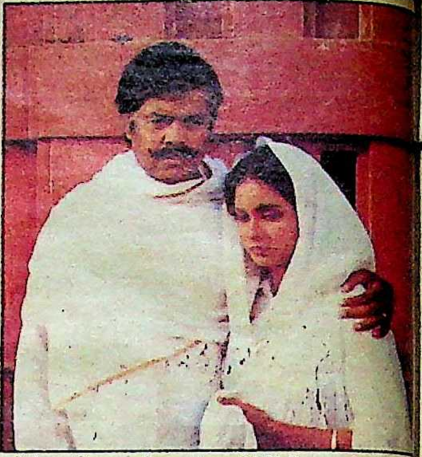

जीवंत अभिनय : फिल्म 'सास्ती' में विजय मोहंती और अपराजिता मोहंती

"रेडी फार टेक...लाइट्स। कट...लाइट्स आफ।" निर्देशक राजू मिश्रा की आवाज गूंजती है। रोशनी बुझ जाती है। उड़िया फिल्म 'चका आंखि सबु देखुची' का यह आखिरी दृश्य फिल्माया जा रहा है। पूरे सेट पर जश्न का माहौल है। राजू मिश्रा की आवाज फिर से गूंजती है—"ओके, लाइट्स।" सुजाता आनंद चरित्र अभिनेत्री की भूमिका इस फिल्म में निभा रही हैं, पर इस सेट पर मौजूद होते हुए भी मानो अनायास वे आज से बीस साल पीछे की स्मृतियों में खो जाती हैं। उन्हें लगता है मानो 'माटी को मनीषा' फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है और पसीने से तरबतर इस फिल्म के निर्देशक मृणाल सेन अब कह रहे हैं—"साइलेंस...साउंड...कैमरा...।" १९६८ में बंगला फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्देशक मृणाल सेन ने 'माटी को मनीषा' नामक अपनी पहली उड़िया फिल्म बनायी थी। सुजाता आनंद इस फिल्म की नायिका थीं और नायक की भूमिका में उनके साथ थे प्रशांत नंदा। वही प्रशांत नंदा जो आजकल मसालेदार फिल्मों के अव्वल दर्जे के निर्माता व निर्देशक माने जाते हैं। प्रशांत की 'लालपान बीबी', 'जगा बरिया' और 'स्वप्न सागर' आदि उड़िया फिल्मों ने अपने समय में धूम मचा दी थी। धूम मचती भी क्यों नहीं, वे तमाम मसाले इस फिल्म में मौजूद थे जो बंबइया हिंदी फिल्मों में भरे होते हैं। इसलिए सुजाता आनंद कभी-कभार प्रशांत से पूछ बैठती हैं, "क्या हो गया है प्रशांत तुम्हें ? उड़ीसा के जीवन और संस्कृति से बहुत दूर हटकर बनीं ये हंगामेदार फिल्में हमारे उड़िया दर्शकों को कहां ले जायेंगी ? मृणाल दा की 'माटी को मनीषा' में तुम्हीं ने इतना भावप्रवण अभिनय किया था न ! " सुजाता आनंद की इन बातों को प्रशांत हंसकर टाल जाते हैं। सुजाता को याद है कि 'माटी को मनीषा' जब 'बर्लिन फिल्म फेस्टिवल' में प्रदर्शित गयी थी, तो वहां लोगों ने विस्मय करते हुए कहा भी था, "क्या उड़िया में भी इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं!" मृणाल सेन की उड़िया में वह पहली और अंतिम फिल्म थी। दरअसल, १९७० के बाद से उड़िया

गुमनामी से उबरने की कोशिश: निर्देशक प्रणब दास

सुखद स्मृतियां ही शेष हैं: सुजाता आनंद

फिल्मों पर बंबइया शैली का इतना तेजी से प्रभाव पड़ने लगा, कि उड़िया संस्कृति और जीवन से जुड़ी फिल्में तेजी से गायब होने लगीं और ऐसी भावप्रवण फिल्में बनानेवाले निर्देशक भी हाशिये पर चले गये। मृणाल सेन भी उड़िया फिल्मों में कुछ अभिनव प्रयोग करने की उत्सुकता से ही आये थे, पर जब उन्होंने माहौल बिलकुल उल्टा देखा, तो दुबारा कभी उड़िया फिल्मों की ओर रुख ही नहीं किया। कलकत्ता और मद्रास के निर्देशक जब तक उड़िया फिल्मों का निर्देशन करते रहे, तब तक ये उड़िया फिल्में उड़िया संस्कृति का प्रतिनिधित्व पूरे दमखम से करती रहीं। मद्रास के निर्देशक केएसडी राव, क्रांति कुमार और मद्रास के ही प्रख्यात निर्देशक सीएस राव ने कई उड़िया फिल्मों का सफल निर्देशन किया। पर १९७० के बाद से उड़िया फिल्मों में काफी बदलाव दीखने लगा। विशेषकर उड़िया निर्देशकों की जमात ने जब निर्देशन का जिम्मा संभाला, तो उड़िया फिल्मों की मूल आत्मा ही भटक गयी। उड़िया के जो गिने-चुने अच्छे निर्देशक भी थे, वे भी न जाने क्यों अपनी पहचान खो बैठे।

ठंडे बस्ते में: निताई पालित! उड़िया फिल्मों के इस बुजुर्ग और सिद्धहस्त निर्देशक को अब कौन पूछता है? निताई ने उड़िया में कई 'ओल्ड क्लासिक' फिल्में बनायीं। निताई पहले उड़िया निर्देशक थे जिन्हें उनकी फिल्म 'मलाजनह' (मृतचंद्रमा) पर सफल निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जब उड़िया फिल्मों से उड़ीसा की सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन की ऊष्मा खतम होने लगी, तो निताई पालित सरीखे निर्देशक भी ठंडे बस्ते में चले गये। पर सिर्फ अकेले निताई ही नहीं, युवा निर्देशक प्रणब दास तथा गोबिंद तेज को भी तो यही भुगतना पड़ा। गुमनामी से उबरने के लिए निताई ने 'केये जीते केये हारे' नामक एक व्यावसायिक फिल्म बनायी। इस फिल्म में उड़िया फिल्मों के स्टार उत्तम मोहंती और विजय मोहंती को उन्होंने लिया। इस फिल्म की नायिका थीं रूपलेखा राय। पर निताई के भाग्य ने फिर साथ नहीं दिया। यह फिल्म चली भी नहीं, क्योंकि आम दर्शकों के बीच यह धारणा घर कर गयी थी कि निताई पालित मसालेदार फिल्म बना ही नहीं सकते। इस तरह व्यावसायिक फिल्म में आजमाइश करके भी निताई असफल रहे।

हाल में लंबी खामोशी के बाद उन्होंने एक फिल्म बनायी है—'रघुअरक्षित' जो उड़िया की एक लोककथा पर आधारित है। यह फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। देखना है रिलीज होने पर इस फिल्म की गति क्या होती है। सुजाता आनंद 'माया' से कहती हैं—"तकनीक के मामले में गुजरे वर्षों में उड़िया फिल्मों ने काफी विकास किया है। पर ज्यों-ज्यों हम साधन से उन्नत होते गये, त्यों-त्यों उड़िया फिल्मों के स्तर का पतन होता गया। बे सिर-पैर की फिल्में बनने लगी हैं। धमाकेदार नाच-गाने, फाइट सीन आदि भरकर फिल्में पेश की जाने लगी हैं। पहले उड़िया फिल्में उड़ीसा की सांस्कृतिक शोभा तथा जीवन के दुख-सुख की प्रतिनिधि थीं। अब सिर्फ ये पैसा कमाने का धंधा भर होकर रह गयी हैं। सचमुच यह उड़ीसा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इन फिल्मों का प्रदर्शन ज्यादातर सिर्फ उड़ीसा तक ही सीमित है। इसलिए ये फिल्में तो यहां के समाज को ही विकृत करेंगी।"

निताई पालित की तरह युवा निर्देशक प्रणब दास भी इन दिनों हाशिये से बाहर आने के लिए व्यावसायिक फिल्मों में हाथ-पांव मार रहे हैं। प्रणब ने एक फिल्म बनायी थी 'हाकिम बाबू'। यह फिल्म उड़ीसा के आदिवासी जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्माता थे अमिय पटनायक। 'हाकिम बाबू' अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी, क्योंकि इस फिल्म में मसाले की कमी थी। इसलिए अमिय बाबू ने अपनी दिशा ही बदल दी। उन्होंने बाद में कई फिल्में बनायीं, लेकिन सभी विशुद्ध व्यावसायिक। १९७६ में उड़िया फिल्मों की दुनिया में आये प्रणब दास ने सबसे पहले मनमोहन महापात्र द्वारा निर्देशित फिल्म 'शीत राति' में संयुक्त निर्देशक की हैसियत से काम किया था। उसके बाद स्वतंत्र रूप से एक फिल्म 'शेष प्रतीक्षा' निर्देशित की। फिर बनायी थी 'हाकिम बाबू'। इस फिल्म को दूरदर्शन पर भी १९८७ में दिखाया गया था तथा १९८६ का इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। पर इस सब के बावजूद प्रणब कहीं के न रहे। इन दिनों प्रणब एक व्यावसायिक फिल्म 'हस लहु भरा दुनिया' का युद्ध स्तर पर निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने उड़िया फिल्मों के प्रमुख सितारों उत्तम मोहंती, विजय मोहंती तथा अभिनेत्री अपराजिता के अतिरिक्त उड़िया फिल्मों के नये-ताजे सितारे मिहिर दास को लिया है। अगर प्रणब की यह फिल्म चल गयी, तो ठीक वरना उनकी भी वही गति होगी जो निताई पालित की हुई थी। निर्देशक गोबिंद तेज भी कमोबेश गर्दिश के दौर में ही हैं। यों गोबिंद तेज की फिल्म 'कावेरी' ने पुरस्कार हासिल किये हैं। हालांकि गोबिंद ने इसमें थोड़ा बहुत मसाला डाला था, पर उतना नहीं जितना आजकल उड़िया फिल्मों में हुआ करता है। लिहाजा, तेज परदे के पीछे चले गये।

कलाकारों का संकट: विजय मोहंती

अभिनेता मिहिर दास

संकट के बादल: उड़िया फिल्मों पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पतन की स्थिति से उड़िया फिल्म उद्योग से जुड़े लोग चिंतित हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इस पतन को रोक पाना आसान नहीं है। यों उड़ीसा सरकार ने उड़िया फिल्मों के विकास के लिए पिछले सात-आठ वर्षों में काफी साधन उपलब्ध कराये हैं और पूरे देश में उड़ीसा ही एक मात्र ऐसा प्रांत है जहां कि सरकार ने फिल्म को बाकायदे उद्योग घोषित कर रखा है। १९८२ में भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार ने फिल्म निर्माता एलवी प्रसाद के साथ साझे में 'कलिंग स्टूडियो' की स्थापना की। पर दो साल पूर्व एलवी प्रसाद के साथ स्टूडियो का पार्टनरशिप खतम हो गया। अब कलिंग स्टूडियो पूरे तौर पर उड़ीसा सरकार का है। यों कलिंग स्टूडियो में अभी तक लैब की व्यवस्था नहीं है। पर इसी वर्ष विगत ८ मई को फिर एलवी प्रसाद की साझेदारी में उड़ीसा की सरकार ने लैब के भवन का शिलान्यास किया है। १९८० के पहले उड़िया फिल्मों को तकनीकी मामलों में पूरी तरह से कलकत्ता, बंबई और मद्रास पर आश्रित रहना पड़ता था। पर कलिंग स्टूडियो बनने के बाद से धीरे-धीरे मोहताजी की यह स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है। निर्देशक प्रणब दास 'माया' से कहते हैं, "यहां के कलिंग स्टूडियो से फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण रमेश सिप्पी और मृणाल सेन जैसी हस्ती ले जाते रहे हैं। साधन से तो हम समर्थ हैं। पर उड़िया फिल्मों के संस्कार को यह साधन भी पतन से नहीं बचा सका।" कलिंग स्टूडियो के प्रबंध निदेशक प्रद्युम्न कुमार मिश्र ने भी स्टूडियो को जमाने में काफी मेहनत की। सरकार ने प्रदेश में 'जनता सिनेमा हाल' के निर्माण हेतु ऋण भी देना शुरू किया। जाहिर है सिनेमा हाल बढ़े, तो उड़िया फिल्मों का व्यवसाय भी बढ़ा। दर्शक भी

बढ़े। फिलहाल छोटे-बड़े सिनेमा हालों को मिलाकर उड़ीसा में तकरीबन ढाई सौ से अधिक हाल हैं।

शुरुआत: उड़िया फिल्मों का इतिहास एक तरह से हिंदी फिल्मों के इतिहास के समानांतर है। १९३३ में जब हिंदी फिल्म 'आलम आरा' का निर्माण हुआ था। तकरीबन उसी समय मोहन सुंदर गोस्वामी ने पहली उड़िया फिल्म 'सीता विवाह' बनायी थी। लेकिन फिल्म निर्माण की गति उड़िया में शिथिल रही। कई-कई साल बाद मुश्किल से एक फिल्म बन पाती थी। यह शिथिलता लगभग १९७० तक बनी रही। पर इस शिथिलता में एक विशिष्टता थी, वह यह है कि इस अवधि में जितनी भी उड़िया फिल्में बनीं, सभी उड़ीसा के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के संस्कार से ओतप्रोत थीं। १९७० के तत्काल बाद एक फिल्म बनी थी 'ममता'। इस फिल्म के निर्देशक थे व्योमकेश त्रिपाठी। यह उड़िया फिल्म 'म्यूजिकल हिट' थी। इस फिल्म में संगीत दिया था प्रफुल्ल कर ने। यों 'ममता' रंगीन फिल्म नहीं थी, पर धूम-धड़ाके के फार्मूले और तेज संगीत के दम पर यह फिल्म ऐसी चली कि उड़िया फिल्मों की मानो दिशा ही बदल गयी। उड़िया की प्रथम रंगीन फिल्म 'गप हवेली सत्त' जो नगेन राय ने निर्देशित की थी, विशुद्ध व्यावसायिक होने के कारण खूब चली थी।

बहरहाल, प्रशांत नंदा और मोहम्मद मोहसिन सरीखे व्यावसायिक उड़िया निर्देशकों ने उड़िया सिनेमा की बागडोर थाम ली। राजू मिश्रा जैसे कैमरामैन भी निर्देशन के क्षेत्र में कूद पड़े। मोहम्मद मोहसिन की 'ममतार डोरी', 'जगा हातरे पगहा' जैसी अनगिनत हिट फिल्में प्रदर्शित हुईं। मोहसिन द्वारा निर्देशित 'विधिर विधान' जो एक साथ बंगला व उड़िया में बनी है, रिलीज होनेवाली है। उड़िया निर्देशकों ने पिछले कुछ वर्षों से द्विभाषी फिल्में (मसलन एक ही फिल्म में बंगला व उड़िया भाषा के संवाद) बनानी शुरू की हैं। ऐसा इसलिए किया है कि अगर फिल्म उड़िया में मार खा गयी, तो पश्चिम बंगाल में कुछ बिजनेस कर लेगी। १९८७ से बंगला-उड़िया की द्विभाषी फिल्मों का दौर तब तेज हुआ, जब उदयशंकर पाणी निर्देशित 'मिच्छ माया संसार' उड़िया में और 'संसार' बंगला में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म उड़ीसा में तो नहीं चली, पर पश्चिम बंगाल में खूब चली। दूसरी फिल्म मोहम्मद मोहसिन की 'विधिर विधान' और तीसरी निर्माणाधीन फिल्म है 'सुना चढ़ेई' जिसका बंगला में नाम है 'जीवन संगिनी'। इस फिल्म को मराठी निर्देशक रवि कीनागी बना रहे हैं। चौथी द्विभाषी फिल्म बनाने जा रहे हैं निर्माता-निर्देशक प्रशांत नंदा। इस फिल्म का नाम है 'या देवी सर्वभूतेषु'। अभिनेता मिहिर दास 'माया' से कहते हैं, "उड़िया व बंगला भाषाओं तथा संस्कृति में क्योंकि काफी कुछ समानता है, इसलिए ऐसी द्विभाषी फिल्में चल जाती हैं।" मिहिर कहते हैं कि बीच में एक चक्कर यह भी चला था कि हिंदी फिल्मों के अनेक निर्माता-निर्देशकों ने हिंदी फिल्मों की उड़िया में 'डबिंग' करके व्यवसाय शुरू कर दिया था। मसलन, ताराचंद बड़जात्या की 'तकदीर' उड़िया में 'डब' होकर 'भाग्य' नाम से प्रदर्शित हुई। ऐसी कई हिंदी फिल्में उड़िया में आयीं। दक्षिण के निर्माता-निर्देशक भी इसकी देखादेखी तमिल-तेलुगू आदि की फिल्मों को उड़िया में डबिंग करवाकर उड़ीसा पहुंचाने लगे। इससे मूल उड़िया फिल्मों के व्यवसाय को काफी क्षति पहुंचने लगी। ऐसी ही फिल्मों ने उड़िया-दर्शकों की रुचि को भी विकृत किया। फिर ये दर्शक उड़िया फिल्मों में ऐसे ही गरम मसाले ढूंढ़ने लगे। निर्देशक राजू मिश्रा ने हिट मसालेदार उड़िया फिल्मों में सबसे ज्यादा नाम कमाया है। राजू मिश्रा की 'ममता मांगे मूल', 'पुअमोर करा ठाकुर' आदि फिल्में काफी चलीं।

कलाकारों की कमी: उड़िया फिल्मों का सबसे बड़ा संकट कलाकारों की कमी है। नायक की भूमिका के लिए उत्तम मोहंती, श्रीराम पंडा, अजित दास तथा विजय मोहंती के ही नाम लिये जा सकते हैं। हाल में मिहिर दास और मुन्ना खां आदि कुछ नये लड़के बतौर हीरो आये हैं। इस तरह कुल मिलाकर पांच-छह लोग ही नायकों की भूमिकाओं में फिट बैठते हैं। नायिकाओं का तो और भी अकाल है। नायिकाओं में महाश्वेता, अपराजिता और तंद्रा तीन ही चर्चित नाम हैं। हाल में एक नयी तारिका वैशाली ने थोड़ी सी जगह बनायी है। उड़िया फिल्मों के चर्चित अभिनेता विजय मोहंती, 'माया' से कहते हैं, "कलाकारों की कमी के कारण 'डेट्स' का भी संकट रहता है। एक फिल्म यहां बनने में तीन-चार महीना लगता है। २० से २५ लाख तक की पूंजी में एक फिल्म तैयार हो पाती है, हां, 'पुअमोर करा ठाकुर' जिसमें मैं ही हीरो था वह २६ लाख की लागत से बनी थी। 'चका आंखि सबु देखुची' उड़ीसा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। इसका ३१ लाख का बजट है। यहां कलाकार भी अधिक पैसे नहीं लेते, हीरो और हीरोइन का रेट एक फिल्म के लिए बस २५ से ३० हजार रुपए तक होता है।

हास्य अभिनेत्रियों का अभाव: साधना दास

विजय मोहंती ने १९८७ में एक उड़िया फिल्म 'भूली हुए ना' का स्वयं निर्देशन किया था। इसमें हीरो थे श्रीराम पंडा तथा हीरोइन थीं—हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रामेश्वरी। यह फिल्म मसाले की कमी के कारण पिट गयी थी। इस फिल्म के निर्माता थे उड़ीसा के शिक्षा मंत्री जदुनाथ दास महापात्र। इस फिल्म की कहानी भी जदुनाथ की ही थी।

उड़िया फिल्मों में भी हिंदी फिल्मों की तरह 'मल्टी स्टार' फिल्मों का प्रयोग किया गया। 'पंच पांडव' में श्रीराम पंडा, उत्तम मोहंती, प्रशांत नंदा, श्रीकांत नंदा, रश्मि आदि सभी दिग्गज उड़िया सितारों की भीड़ जमा कर दी गयी, पर यह फिल्म नहीं चल पायी। पार्श्व संगीत के मामले में उड़िया फिल्में अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकी हैं। बंबई पर ही इसके लिए आश्रित रहना पड़ता है। उड़ीसा में पुराने संगीत निर्देशकों में अक्षय मोहंती ही ले देकर हैं। गायकों में प्रणब पटनायक, श्रीकांत दास, विभु, गीता दास और तानी प्रमुख हैं। उड़िया फिल्मों में खलनायकों की भी कमी है। इनमें नेत्रानंद मिश्र और असितपति प्रमुख हैं। हास्य अभिनेत्री साधना दास 'माया' से कहती हैं, "हास्य कलाकारों की भी कमी है। हास्य अभिनेत्रियों में मेरे अलावा बस एक और अभिनेत्री मामिना हैं।"

उड़िया फिल्मों का व्यावसायिक क्षेत्र यों तो ज्यादातर उड़ीसा तक ही सीमित है, पर बिहार के कुछ नगरों, कलकत्ता, खड़गपुर, और आंध्र-प्रदेश तथा उड़ीसा की सीमा पर स्थित आंध्र के कुछ शहरों में भी ये फिल्में थोड़ा-बहुत चल जाती हैं। पर सवाल उठता है कि उड़िया फिल्मों के पतन का कारण क्या है? सरकारी प्रोत्साहन मिलने और फिल्म निर्माण की संख्या में वृद्धि होने के बाद भी नये कलाकार क्यों नहीं तैयार हो रहे? उड़ीसा जैसे गरीब और पिछड़े प्रांत में बेशक ये उड़िया फिल्में युगांतरकारी भूमिका निभा सकती थीं, पर हुआ इसके विपरीत। हिंदी फिल्मों के बजाय इन क्षेत्रीय फिल्मों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय फिल्में अपने सामाजिक जीवन की पीड़ा को सार्थक स्वर भी देने का काम कर सकती हैं और राष्ट्रीय फलक पर किसी कोने में ही सही, पर अपने क्षेत्र की सम्मानजनक पहचान भी स्थापित कर सकती हैं। पर उड़िया फिल्मों को इन उद्देश्यों से कोई सरोकार नहीं। जब इनकी हैसियत नहीं थी, तब इनमें भरपूर चेतना छलकती थी। पर आज चेतना से इनका कोई वास्ता नहीं। उड़िया चेतना को कुंद करने का काम ये फिल्में अवश्य कर रही हैं। अभिनेता मिहिर दास कहते हैं, "उड़िया फिल्मों की दर्शक औरतें ज्यादा हैं। औरतों को आंसू चाहिए। आंसू! फिल्म में जो निर्देशक सबसे ज्यादा आंसू गिरवा सकता है, वही सफल है।" मिहिर की बात शायद सच हो, पर उड़िया फिल्मों की इस दुर्दशा पर आज आंसू कौन बहायेगा?

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

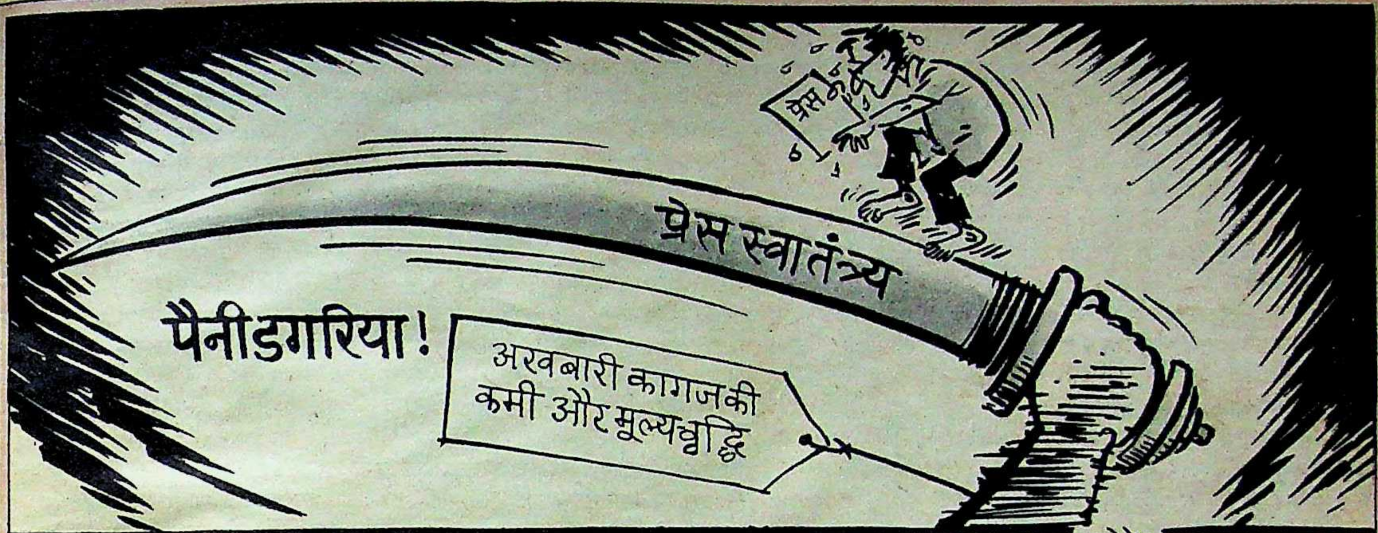
प्रेस
प्रेस स्वातंत्र्य
पैनीडगरिया!
अखबारी कागज की कमी और मूल्यवृद्धि

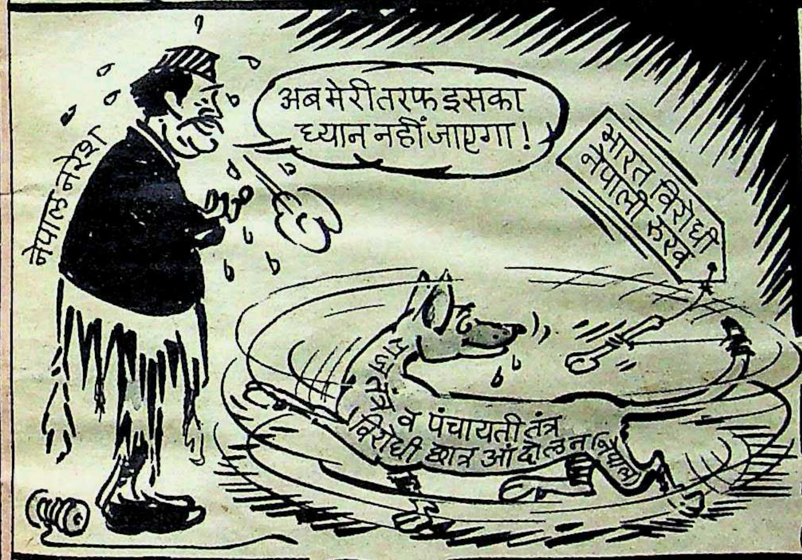
नेपाल नरेश
अब मेरी तरफ इसका ध्यान नहीं जाएगा!
भारत विरोधी नेपाली रुख
प्रजातंत्र व पंचायती तंत्र विरोधी छात्र आंदोलन (नेपाल)

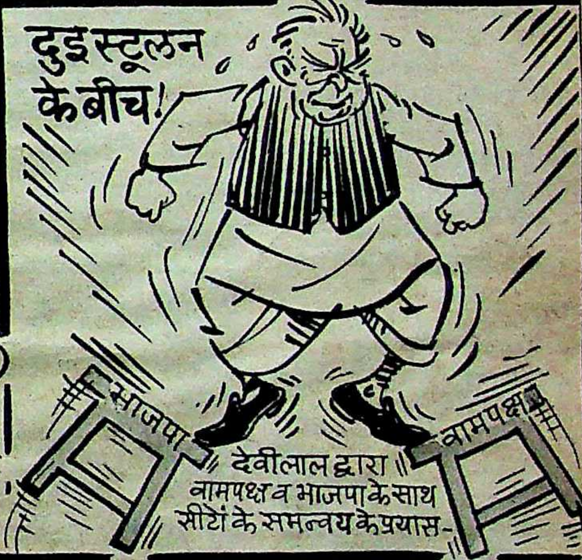
दुइ स्टूलन के बीच!
भाजपा
वामपक्ष
देवीलाल द्वारा वामपक्ष व भाजपा के साथ सीटों के समन्वय के प्रयास-

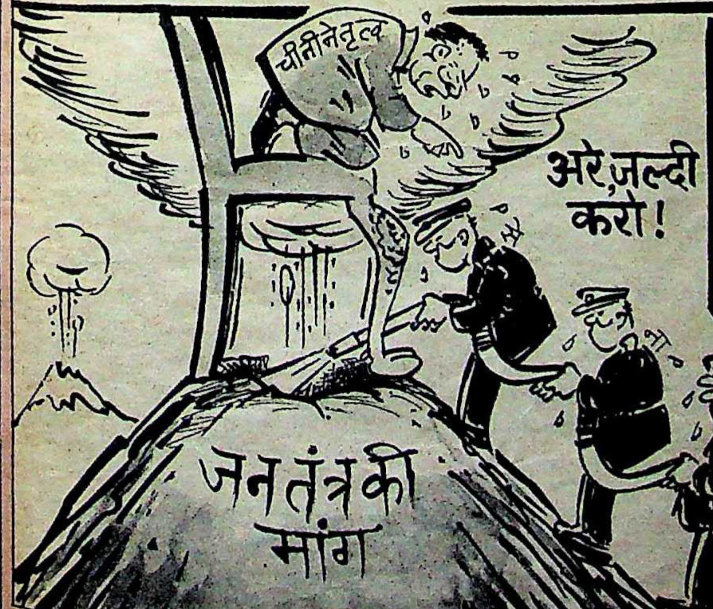
चीनी नेतृत्व
अरे, जल्दी करो!
जनतंत्र की मांग

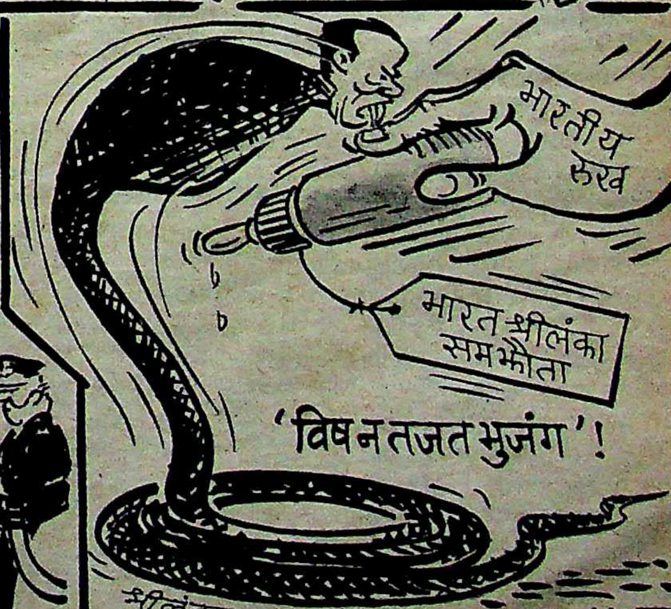
भारतीय रुख
भारत श्रीलंका समझौता
'विष न तजत भुजंग'!
श्रीलंका का रुख
काक

Digitized by Chennai and eGangotri

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

जुलाई द्वितीय अंक

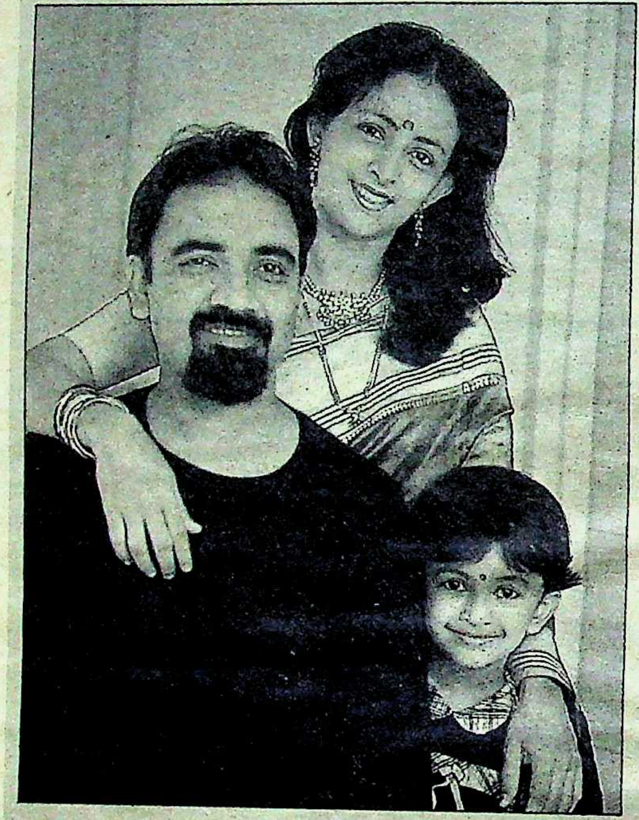

आवरण कथा :

क्या आप जानती हैं आपका दाम्पत्य सुख किस खतरे में है ?

अंक के विशेष आकर्षण :

- शादी करो तो मुश्किल, न करो तो मुश्किल
- बात करना भी एक कला है
- अपनी दोस्ती में ईमानदार बनिए
- आत्महत्या से स्त्री जाति की स्थिति नहीं सुधर सकती
- बैंकिग दुनिया की प्रथम महिला जनरल मैनेजर
- मेरी सुहागरात : तन का नहीं, मन का अभिषेक
- कथा साहित्य : नवेन्दु घोष की लम्बी कहानी 'कंचन, कामिनी और एक योगी' की दूसरी किस्त
- 'उपहार' : एक रोचक काफी-ब्रेक लघुकथा

साथ ही अन्य सभी स्थाई स्तंभ।

छबरिया परेशानी में

मनोहर छबरिया मुश्किल में फंस गये हैं। खाड़ी के देशों में कमाल की कामयाबी हासिल करनेवाले छबरिया प्रवर्तन एजेंसियों से घिर गये हैं। पांच साल में ही कंपनियों की धड़ाधड़ खरीद से भारत में ६०० करोड़ रु० का साम्राज्य खड़ा कर लेनेवाले इस नौजवान व्यवसायी से प्रवर्तन निदेशालय ने जांच अधिकारियों के सामने हाजिर होकर अपनी हैसियत और अपने पैसे का स्रोत बताने को कहा है।

> “
>
> केंद्रीय उत्पाद कर अधिकारियों ने भी उनकी दो कंपनियों 'ओरसन' और 'निहान इलेक्ट्रानिक्स' को कारण बताओ नोटिस भेजी है। उन पर १५ करोड़ रु० के उत्पाद कर की चोरी का आरोप है। अपने प्रबंधकों द्वारा पैसे में हेराफेरी करने के कारण ये कंपनियां पहले से ही मुश्किल में हैं।
>
> ”

केंद्रीय उत्पाद कर अधिकारियों ने भी उनकी दो कंपनियों 'ओरसन' और 'निहान इलेक्ट्रानिक्स' को कारण बताओ नोटिस भेजी है। उन पर १५ करोड़ रु० के उत्पाद कर की चोरी का आरोप है। अपने प्रबंधकों द्वारा पैसे में हेराफेरी करने के कारण ये कंपनियां पहले से ही मुश्किल में हैं।

चर्चा है कि छबरिया ने भारत में निवेश करने के लिए विदेशों में भारी कर्जे लिए हैं। भारत की तुलना में विदेशों में सूद की दरें काफी कम हैं, ऐसे में अप्रवासी भारतीय वहां से कर्ज लेकर भारत में निवेश करते रहे हैं। लेकिन छबरिया के फंसने का सबब यह है कि भारत में उनके निवेश पर कमाई निराशाजनक रही और रुपए का पिछले महीनों में अवमूल्यन होता चला गया।

विवाद सुलझा

ऐसा लगता है कि डीसीएम का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। कहा जाता है कि पिछले महीने हुए प्रबंधक मंडल की बैठक में तीन परिवारों के बंटवारे का विवाद फिलहाल तो सुलझा दिया गया, लेकिन अभी भी अंतिम समय में विवाद पैदा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार की भरतराम शाखा को दो अन्य शाखाओं के लोग ८ करोड़ रु० देंगे, जबकि इस परिवार के पास पड़े शेयर आपसी सहमति से तय मूल्य पर दो अन्य शाखाओं को दे दिये जायेंगे।

जो हो, इस विवाद ने पिछले कुछ वर्षों में डीसीएम को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। पहले उत्तर भारत की एक नंबर की यह कंपनी श्रीराम परिवार को देश के १० प्रमुख औद्योगिक घरानों में भी शामिल कराये हुए थी। अब उस स्थिति को पाने के लिए इसके कर्ताधर्ताओं को दोगुना श्रम करना पड़ेगा। यह समूह कई सुनहरे मौके भी खो चुका है। यह अभी भी चींनी और सूती कपड़े जैसे पुराने कारोबार में ही फंसा है। इसकी कंप्यूटर कंपनी भले ही देश में पहल करनेवाली कुछ कंपनियों में से एक हो, लेकिन यह भी सफल नहीं रही।

सबसे बड़ा निजी निवेश

अगले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित कारखाने में होने जा रहा है। देश की यह सबसे बड़ी कंपनी अगले छह वर्षों में अपने प्लांट के विस्तार और आधुनिकीकरण पर २७०० करोड़ रु०/— जवाहर रोजगार योजना की लागत से अधिक— खर्च करने जा रही है। इससे इसकी उत्पादन-क्षमता २४ से ३० लाख टन हो जायेगी जो मूल १० लाख टन क्षमता की तीन गुनी होगी।

टाटा समूह अपने अन्य कंपनियों का विस्तार भी कर रहा है। टाटा केमिकल्स ने हाल में ही टाटा फर्टिलाइजर्स को ले लिया है। टेल्को, 'टाटा टर्बो' नामक नया पैसेंजर चेसिस बनाने जा रही है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश में एक नयी फैक्टरी भी लगा रही है। बंबई में और उसके आसपास बिजली कंपनियों की क्षमता बढ़ाने की योजना भी है। साथ ही करनाल में संयुक्त क्षेत्र में तेलशोधक कारखाना लग रहा है।

अगर ये सारी योजनाएं पूरी हो जाती हैं, तो अगले चार-पांच वर्षों में ही टाटा समूह का कारोबार १०००० करोड़ रु० से ऊपर पहुंच जायेगा। और तब यह बिड़ला, अंबानी और अन्य सभी घरानों से काफी आगे निकल जायेगा।

हवाई टैक्सी

थापर समूह एक अप्रवासी भारतीय के साथ मिल कर देश में पहली वायु टैक्सी सेवा आरंभ करने जा रहा है। इसके सहयोगी अप्रवासी ने एक 'डी हैविलैंड १२८' जेट विमान भेज भी दिया है जो दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़ा है।

थापर के अलावा हिंदुजा, विजय माल्या और कुछ अन्य अप्रवासी भारतीय भी वायु टैक्सी सेवा शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सरकार के पास ऐसी सात अर्जियां पड़ी भी हैं। कहते हैं, ऐसी परियोजनाओं में विश्व बैंक भी दिलचस्पी ले रहा है और वह इसके लिए कर्ज दे सकता है।

टीवी बाजार में मंदी

बाजार में प्रतिद्वंद्विता बढ़ने के साथ ही टीवी बाजार में गर्मी आती जा रही है। एक अर्धसरकारी संस्था एनसीएईआर द्वारा हाल में कराये गये एक सर्वेक्षण के परिणाम देखकर बाजार की अगुवा कंपनियों के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। पिछले साल १० लाख से अधिक टीवी सेट बिके, जिनमें बीपीएल और ओनिडा सबसे आगे थे। बीपीएल का बाजार के १२ फीसदी और ओनिडा का १० फीसदी हिस्से पर कब्जा था।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब टीवी बाजार का बढ़ना रुक गया है।

> “
>
> विशेषज्ञों का कहना है कि अब टीवी बाजार का बढ़ना रुक गया है। १९८४ में रंगीन टीवी के बाजार की विकास-दर ५०० फीसदी थी। १९८५ में यह १४० फीसदी हो गयी थी और पिछले साल तो सिर्फ १५ फीसदी रह गयी। पिछले एक साल में ही मुनाफे की दर में २५ फीसदी गिरावट आ गयी है।
>
> ”

१९८४ में रंगीन टीवी के बाजार की विकास-दर ५०० फीसदी थी। १९८५ में यह १४० फीसदी हो गयी थी और पिछले साल तो सिर्फ १५ फीसदी रह गयी। पिछले एक साल में ही मुनाफे की दर में २५ फीसदी गिरावट आ गयी है। बाज़ार से कुछ ब्रांड विदा हो चुके हैं, जबकि अनेक दूसरों को अपना अस्तित्व बचाने में मुश्किल पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो आधी कंपनियां अपना बोरिया-बिस्तर समेट लेंगी।

—डा० जय दुभाशी

महाकोला की भिड़ंत पेप्सीकोला से

अब यह तय हो चुका है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सीकोला अगले साल से भारत में अपना कारोबार शुरू कर रही है। इससे भारत के शीतल पेय बाजार में कैसा उबाल आया हुआ है ?

Thums Up
Thums Up

उपभोक्ता को लाभ या झांसा ? : महाकोला

नाम तो है, 'शीतल पेय', लेकिन इन गर्मियों में शीतल पेय बाजार में उबाल आया हुआ है। भारत में पेप्सीकोला के प्रवेश का आतंक तो छाया ही हुआ है, साथ ही शीतल पेय उद्योग में वर्चस्व के लिए घमासान संघर्ष भी जारी है। वर्ष १९८८ में शीतल पेय बाजार में कुल छह सौ करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस क्षेत्र में 'लिटल मेन' के रूप में चर्चित पारले प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रमेश चौहान ने 'थम्स अप' के इंटरनेशनल साइज को 'महाकोला' के नाम से बाजार में लाकर हंगामा खड़ा कर दिया है। इसके जरिए चौहान ने न केवल मौजूदा प्रतिद्वंद्वी शीतल पेय कंपनियों को पछाड़ दिया है, बल्कि अगले साल बाजार में उतरनेवाले पेप्सीकोला से भी दो-दो हाथ करने की तैयारी कर ली है।

महाकोला का वर्चस्व : वैसे ६०० करोड़ रुपए के इस बाजार के ४४ फीसदी हिस्से पर पारले का कब्जा है, लेकिन बाजार में नये उतरे डबलकोला और मैकडावेल जैसे ब्रांडों ने उसकी स्थिति कमजोर कर दी थी। इसके अलावा दिल्ली क्षेत्र के प्रतिष्ठावाले बाजार में पारले का 'थम्स अप' प्योर ड्रिंक्स के कैंपाकोला से पिछड़ा ही रहा था। लेकिन बाजार के सारे गुरों को जानने के लिए विख्यात चौहान ने महाकोला के जरिए दिल्ली के कोला बाजार पर चरणजीत सिंह के कैंपाकोला की पकड़ कमजोर कर दी है।

पारले एक्सपोर्ट्स के दिल्ली स्थित कमर्शियल मैनेजर थामस चांडी कहते हैं, "हम दिल्ली में उपभोक्ताओं तक पहुंचने की विपणन की सारी योजनाएं अपनाकर हार चुके थे।" लेकिन चौहान इस बात से इनकार करते हैं कि किसी अन्य ब्रांड को बाजार से खतम करने के लिए ही महाकोला को लाया गया है। उनका कहना है, हम सिर्फ थम्स अप की छवि को बेहतर बनाना चाहते हैं।" मंशा चाहे जो रहा हो, महाकोला को बाजार में उतारने का असर बहुत ही तेज और भारी रहा है। मसलन पहले दिल्ली में कैंपाकोला के ५६ लाख केस बिकते थे, जबकि थम्सअप (पुराने बोतल में) के सिर्फ ७ लाख केस। लेकिन २५० मिली लीटरवाले महाकोला के बाजार में उतरते ही कैंपा और थम्स अप का अनुपात आठ और एक की जगह, चार और एक का हो गया है।

निश्चित रूप से पारले इससे उत्साहित है और वह अन्य नगरों में भी महाकोला उतारने की योजना बना रही है। यह सफलता मिलनी ही थी, क्योंकि कीमत तो ३ ही रुपए रखी गयी, जबकि ग्राहक को ५० मिली लीटर पेय और मिल गया। पारले के प्रतिद्वंद्वी इस बात को लेकर और परेशान हुए कि नया माल बाजार में लाने के ठीक पहले रमेश चौहान ने अन्य सभी शीतल पेय निर्माताओं के साथ मिलकर २०० मिली लीटर वाले शीतल पेय के बोतल की कीमत २.५० रुपए से बढ़ाकर ३ रुपए करने का फैसला कराया था। और उस फैसले के तुरंत बाद उन्होंने महाकोला लाकर बाजार में भारी उलटफेर कर दिया है।

शीतल पेय उद्योग के सूत्रों के अनुसार २०० मिली लीटर वाली बोतलों की जगह २५० मिली लीटर वाली बोतल लाने का खर्च चौहान ने खुद उठाया है। पुरानी बोतलें पारले के क्षेत्रीय विक्रेताओं के पास जमा पड़ी हैं। चांडी इसका खंडन करते हैं और बताते हैं कि २५० मिली लीटरवाली बोतल का खर्च

क्षेत्रीय वितरकों ने उठाया है। अपने माल को बोतल बंद करनेवालों के साथ मिलकर चौहान ने कुछ दिनों तक २०० मिली लीटर की बोतलों में थम्स अप भेजना रोक दिया। ऐसा खाली बोतलों को बाजार से वापस जुटा लेने के लिए किया गया। सूत्रों के अनुसार अपने नये माल को बाजार में अच्छी स्थिति में पहुंचा देने के लिए पारले ने खुदरा विक्रेताओं को एक क्रेट माल ७५ रुपए की जगह ६० रुपए में ही देना शुरू किया, जिससे उनकी कमायी बढ़ गयी। खुदरा विक्रेता बताते हैं कि अगर वे महाकोला नहीं बेचते, तो कंपनीवाले उन्हें अपने ही यहां बना लिम्का, माजा और गोल्ड स्पाट नहीं देते। इन तीनों की जबरदस्त मांग है और जिस निर्माता की मुट्ठी में खुदरा विक्रेता आ जायें, आधी लड़ाई, तो वह वैसे ही जीत लेता है।

विज्ञापन अभियान: अपनी स्थिति को मजबूत करने के पुख्ता इंतजाम के तहत पारले ने जोरदार विज्ञापन अभियान भी छेड़ दिया है। खुद 'महाकोला' नाम भी नव धनाढ्यों के लिए बेहद आकर्षक है, जिनका अब महानगरों में बोलबाला हो चुका है। यह नाम सुझानेवाली पारले की विज्ञापन एजेंसी, एम्बिरंस ने भी लगता है कि शहरी मध्यम वर्ग के स्वदेशी संस्कारों को भुनाने के लिए यह नाम सुझाया था। पेप्सी कोला जैसे विदेशी नाम का मुकाबला करते समय 'महाकोला' का 'महा' शब्द स्वदेशीपन का प्रतीक बन सकता है। महाभारत की सफलता ने भी 'महा' शब्द को लोकप्रिय बना दिया है।

कोला बाजार में अपनी हिस्सेदारी घटती देखकर पहले से जमी कंपनियां एकदम अफरातफरी में आ गयी हैं। दिल्ली में कैंपाकोला ने जबरदस्त आक्रामक जवाबी विज्ञापन अभियान शुरू किया है, जबकि आमतौर पर प्योर ड्रिंक्स के चरणजीत सिंह बहुत प्रचार पाने से दूर ही रहा करते हैं। बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर और अखबार-पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर उन्होंने—'कौन कोला सबसे अधिक बिकता है?' या 'साइज से बढ़िया स्वाद' नारे उछाले हैं। इस जवाबी अभियान पर कितना खर्च आ रहा होगा, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखबारों में आनेवाले कैंपा के विज्ञापन का आकार ३३ इंच × १६ इंच का है और एक अखबार इस के लिए ७०,००० रुपए वसूल करता है।

लेकिन चांडी इन नारों को भी चुनौती देते हैं और कहते हैं कि स्वाद भी कई चीजों से जुड़ा है। ग्राहक के लिए पैसा भी बड़ी चीज है। अगर मान भी लें कि उसे कैंपाकोला का स्वाद पसंद है, लेकिन वह मूल्य और मात्रा पर भी तो गौर करेगा। अगर यह बात सही है, तो चौहान बड़ी आसानी से यह मुकाबला जीत लेंगे, क्योंकि वे बिना एक भी पैसा अतिरिक्त लिये हुए उपभोक्ता को ५० मिली लीटर अधिक शीतल पेय दे रहे हैं।

> कोला बाजार में अपनी हिस्सेदारी घटती देखकर पहले से जमी कंपनियां एकदम अफरातफरी में आ गयी हैं। दिल्ली में कैंपाकोला ने जबरदस्त आक्रामक जवाबी विज्ञापन अभियान शुरू किया है।

पारले ने इस प्रकार भविष्य में पेप्सीकोला से हो सकनेवाले संभावित नुकसान से बचने की तैयारी कर ली है। तथापि पारले के अधिकारी इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोकाकोला और पेप्सीकोला के स्टैंडर्ड साइज की बोतल में अपना कोला बेचना शुरू करके पारले ने दरअसल यही किया है। महाकोला के विज्ञापन में भी इंटरनेशनल साइज में कोला उपलब्ध कराने की बात खास जोर देकर कही जाती है। लेकिन चौहान इस आरोप का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि हो सकता है कि वे ३०० या ३५० मिली लीटर की बोतल भी ले आयें। लेकिन क्या यह कीमत के हिसाब से चल पायेगी?

पेप्सीकोला की तैयारियां: पेप्सीकोला का मुकाबला करना सरल नहीं है। यद्यपि स्वदेशी माल के साथ राष्ट्रीय भावना भी जुड़ी रहती है, लेकिन देश में विदेशी माल के प्रेमियों की भी कमी नहीं है। भारतीय बाजार के लिए जिन पेय और खाद्य पदार्थों के निर्माण की स्वीकृति पेप्सीकोला ने भारत सरकार से ली है, उनकी सूची देखकर ही अंदाजा लग सकता है कि पेप्सीकोला शीतल पेय बाजार के लिए न केवल एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता है, बल्कि वह अन्य सबको पछाड़ भी सकता है। सूत्रों के अनुसार पेप्सीकोला प्लास्टिक के हल्के क्रेटों और बोतलों में अपना माल उतारने की योजना बना रही है। ३० बोतलोंवाला क्रेट ११० रुपए में बिकेगा। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य खुदरा बिक्री-केंद्रों पर डिस्पेंसर और बूथ लगाने की भी इसकी योजना है। ये ऐसे आकर्षण हैं, जिनके बल पर पेप्सीकोला भारतीय बाजार में छा सकता है।

चौहान को शायद एक अन्य मोर्चे पर भी मुकाबला करना पड़ा सकता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार आयोग के पास पारले के खिलाफ दो शिकायतें आयी हैं। संयोग से दोनों शिकायतें एक ही साथ पहुंचीं और दोनों में बहुत कुछ समानता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून की धारा १२ के तहत दायर शिकायत में आरएस भनचंदा और एमएस तलवार ने कहा है कि छोटी बोतलवाली कीमत पर ही बड़ी बोतल में अधिक कोला देना ग्राहकों का 'शोषण' करना है। एक शिकायती चिट्ठी में कहा गया है, "पुरानी कीमत पर ही उसी माल की अधिक मात्रा देना किसी परोपकारी या संन्यासी आदमी का काम तो हो सकता है, लेकिन किसी व्यापारी का नहीं। वह ऐसा काम शोषण के मंशा से ही करेगा।"

बहरहाल पारले के अधिकारियों का मानना है कि ये शिकायतें उनकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की साजिश है, लेकिन चौहान कहते हैं, "यह शिकायत तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है।" यह समझ पाना मुश्किल है कि अगर उपभोक्ता को कम कीमत पर अधिक माल मिल रहा है, तो किसका शोषण हो रहा है। चांडी कहते हैं, "यह शिकायत बेहूदा है। क्या कोई उपभोक्ता उसी कीमत पर अधिक माल मिलने की शिकायत करेगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं?"

दरअसल, सारे मामले में विवाद का असली मुद्दा यही है। कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि पारले कम कीमत पर अधिक कीमत का माल दे सकता है। इससे यही संकेत मिलता है कि महाकोला के पूर्व पारले उपभोक्ताओं का शोषण करता रहा था, अथवा आज जो निर्माता तीन रुपए में २०० मिली लीटर शीतल पेय बेच रहे हैं, वे उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि तब उपभोक्ता सवाल कर सकते हैं कि जितनी कीमत में पारले जितनी मात्रा में शीतल पेय दे रहा है, उस हिसाब से अन्य निर्माता अपना शीतल पेय क्यों नहीं बेचते। उस उद्योग के सूत्रों के अनुसार, "थोक विक्रेता को २४ बोतलों के एक क्रेट में ६ रुपए का लाभ होता है, लेकिन बोतल का आकार बढ़ जाने के कारण शीतल पेय की बढ़ी हुई मात्रा की कीमत को लाभ में से घटाया जाये, तो थोक विक्रेता का लाभ ढाई रुपए कम होकर साढ़े छह रुपए रह जायेगा, लेकिन महाकोला की बिक्री से थोक विक्रेता का नहीं, बल्कि निर्माता पारले कंपनी का लाभ कम होता है, क्योंकि 'महाकोला' की बढ़ी हुई मात्रा का खर्च निर्माता कंपनी ही वहन कर रही है। ऐसी स्थिति तो तब है, जबकि सरकार से यह शिकायत है कि उसने उत्पाद कर अनापशनाप बढ़ा दिया है। इसलिए इस बात पर मतभेद बना रहेगा कि किसका शोषण हो रहा है, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि बाजार में शीतल पेय की मांग बराबर बनी रहेगी, फिर चाहे इसकी पूर्ति पेप्सीकोला, थम्स अप करे या कैंपाकोला। महाकोला बाजार में आये या न आये, प्यास तो बराबर बनी ही रहेगी।

—सुधा भाटिया

चाहिए एक आदर्शवादी रिमोट कंट्रोल

इक्कीसवीं सदी में कामयाब होने के लिए पूरे माहौल पर कंप्यूटर शिक्षा हावी है। बच्चे इस पर खास ध्यान दे रहे हैं। खुशी और हैरानी होती है जब आठ-आठ साल के बच्चे इतने आत्मविश्वास और उत्साह के साथ कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करते हैं और जल्द-से-जल्द, ज्यादा-से-ज्यादा सीखना चाहते हैं। कंप्यूटर तकनीकी की बारीकियां उन्हें, इतिहास भूगोल की पुस्तकों में लिखे बेजान अध्याय की अपेक्षा जल्द याद होती हैं। जमाना कुछ इस कदर बदला है कि बच्चे खेल खिलौनों में भी रिमोट कंट्रोल से संचालित खेल पसंद करते हैं।

यह 'रिमोट कंट्रोल' शब्द पहली बार मैंने कई साल पहले सुना था। हमारे एक चित्रकार मित्र हमदम का उन दिनों पहला पहला प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी प्रेमिका किसी स्कूल में व्यायाम सिखाती थी। वे दोनों जल्द-से-जल्द विवाह सूत्र में बंधना चाहते थे। दोस्तों की मदद से एक दिन गुरुद्वारे में उन दोनों ने शादी कर ली। पूरे दिन बधाइयों-मिठाइयों का दौर चला, लेकिन शाम होते-होते लड़की की हिम्मत जवाब दे गयी। वह रोने लगी, "मैं घर जाऊंगी।" हम सबने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी। एक ही रट ले बैठी, "मेरे मम्मी-पापा चिंता करेंगे, मुझे घर जाना है।" हमदम डरपोक नहीं था, पर वह गुरदीप की बेचैनी का लिहाज करना जानता था। वे लगभग एक साल तक इसी तरह विवाहित रहे। गुरदीप तीन बजे स्कूल से हमदम के कमरे पर आ जाती। वे दो घंटे साथ रहते। पांच बजे हमदम उसे घर छोड़ आता। हमदम दोस्तों से कहता, "हमारी तो रिमोट कंट्रोल शादी है। असलियत से ज्यादा हम खयालों में करीब हैं।" इसी तरह उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनायी। शादी को एक साल हो गया, लेकिन दाम्पत्य का पहला दिन भी शुरू न हुआ।

आजकल शादी के बाद अलग-अलग रहना कोई अनहोनी बात नहीं है। नौकरी की मजबूरियां, तबादले की तंगी, मकान की समस्या, बढ़ती महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी मोहलत नहीं देतीं कि पहले दिन से साथ-साथ रहा जाये। कई विवाहित जोड़ों का दाम्पत्य मेडिकल लीव के सहारे ही चलता रहता है। अंततः जब साथ रहने का वक्त आता है, तो प्रायः पत्नी को ही नौकरी छोड़नी पड़ती है या लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है। ऐसे संबंधों में कई बहुत अच्छी बातें होती हैं—एक तो विवाह के तत्काल बाद तालमेल के नाम पर एक दूसरे को व्यक्तित्वविहीन बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती, दूसरे अति-दाम्पत्य से उपजा ठंडापन रिश्तों को ठिठुराता नहीं है, तीसरे पति-पत्नी एक दूसरे के कार्य-क्षेत्र की ताकत और कमजोरियां दोनों को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को महसूस होता है कि पति के जीवन में उसकी जगह महज खाना बनाने वाली मिसरानी की नहीं, बल्कि सपनों की रानी की है। जीविका के क्षेत्र में हासिल की गयी कार्यकुशलता में भी कोई व्यवधान नहीं पड़ता।

रिमोट कंट्रोल प्रणाली को वर्षों पहले हमारी दादी-नानी ने बड़ी अच्छी तरह से आत्मसात किया था, इसके सबूत आज भी देखने को मिल जाते हैं। वे घर के पिछवाड़े के कमरे में बैठी-बैठी पूरे परिवार की गतिविधियों का लेखा-जोखा रखतीं : कौन बच्चा पढ़ने में मन लगा रहा है, कौन नहीं, किसकी आदतें कैसी बन रही हैं, किसकी गृहस्थी में कैसी समस्याएं हैं, उन्हें सब पता रहता। उसी हिसाब से वे फरमान जारी करतीं। किसी की हिम्मत न होती कि उनकी मर्जी के खिलाफ आचरण करे। अपनी चारपाई पर बैठे-बैठे वे समूचे लंबे-चौड़े परिवार का नेतृत्व संभालतीं और खाली वक्त में गोमुखी में हाथ डाल रामनाम भी जप लेतीं। वे परिवार की हाईकमान थीं। जीते जी परिवार की नब्ज पर उनकी पकड़ बनी रहती और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा, परिवार को अनुशासन और एकता के सूत्र में बांधे रहती। आजकल की स्त्रियां चाहें तो अपने बुजुर्गों से यह गुर सीख सकती हैं कि नेपथ्य में रहकर केंद्रीय भूमिका का निर्वाह कैसे किया जाये।

हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिनों में संघर्ष और बलिदान, सत्य और अहिंसा, प्रेम और साहस जैसी दुर्लभ प्रवृत्तियों का जन-जन में संचार इसी रिमोट कंट्रोल पद्धति से महात्मा गांधी ने किया था। मैं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शांतिदेवी से बात करती हूं तो वे कहती हैं, "गांधीजी हर जगह मौजूद नहीं रहते थे, फिर भी हम लोग उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करते थे। आश्रम में मुंह अंधेरे उठना, प्रार्थना करना, चरखा चलाना, बच्चों को पढ़ाना और बस्तियों में जाकर लोगों को आजादी का मतलब और मकसद समझाना, हमारा रोज का काम था। यह नहीं कि जिन दिनों गांधीजी आश्रम में नहीं हैं, उन दिनों काम की छुट्टी।"

शांतिदेवी संस्मरणों का खजाना हैं। जब मैं कुछ क्रांतिकारी स्त्री-नेताओं के नाम लेती हूं, वे भड़क जाती हैं, "बस इतनी है तुम्हारी जानकारी। अरे आजादी की लड़ाई में हम हजारों की तादाद में थीं, हजारों की। जब गिरफ्तारी होती थी, बहनों में होड़ लगती थी, कौन पहले जेल जाये। भर जाती थीं जेलें। स्वाधीनता संग्राम में औरतें कतई पीछे नहीं थीं, ये तो बाद में जब गद्दी मिली, तो मर्द उछल-उछल कर आगे आ गये। हमने कभी इसकी कीमत वसूल करने की सोची ही नहीं। आज जिस तरह कुरसी पाने की होड़ लगी है, उस समय कुरसी छोड़ने की होड़ लगी थी। जाने कितनों ने अपनी नौकरियां छोड़ीं, व्यापार छोड़े। किसी ने यह नहीं सोचा कि हम भूखे मर जायेंगे, हमारे बाल-बच्चों का क्या होगा। हमारे पतिदेव ने स्कूल की नौकरी छोड़ी, तब हमारा बड़ा बेटा ढाई साल का था। उन्होंने कहा, "तुम भी महिलाओं के साथ जाकर शराब की दुकानों पर धरना दो। साथ-साथ जेल जायेंगे, तो कष्ट कम होगा। मुन्ने को भी ले जायेंगे।"

शांतिदेवी को दुख है कि आज सत्य और प्रेम की प्रेरणा-शक्ति से लोग संचालित नहीं हो रहे, शक और नफरत से हो रहे हैं। यही आतंकवाद और हिंसा का मुख्य कारण है।

"इसे खतम करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है?"

"है क्यों नहीं? एक बार फिर कोई गांधी आये और सारे देश को एक जीवन-मंत्र दे जाये, जैसे चरखा, जैसे खादी, फिर देखो कैसे बदलते हैं लोग।"

मैं यकीन नहीं कर पाती "क्या हिंसक तत्वों पर इस मंत्र का कोई असर होगा?"

"क्यों नहीं?" शांतिदेवी पूरे जोर से कहती हैं "आज ये लोग कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर अलगाव की बात कर रहे हैं। जब देश से लगाव हो, तो अलगाव की बात सब भूल जायेंगे। मेरा कहना है, पहले लगाव तो पैदा करो लोगों में।"

मैं उतनी आश्वस्त नहीं हूं पर शांतिदेवी की दृढ़ता से लगता है ऐसा हो सकता है, प्रेम और सद्भाव का रिमोट कंट्रोल एक बार पकड़ में आ जाये।

—ममता कालिया

रिमोट कंट्रोल प्रणाली को वर्षों पहले हमारी दादी-नानी ने बड़ी अच्छी तरह से आत्मसात किया था, इसके सबूत आज भी देखने को मिल जाते हैं। वे घर के पिछवाड़े के कमरे में बैठी-बैठी पूरे परिवार की गतिविधियों का लेखा-जोखा रखतीं : कौन बच्चा पढ़ने में मन लगा रहा है, कौन नहीं, किसकी आदतें कैसी बन रही हैं, किसकी गृहस्थी में कैसी समस्याएं हैं, उन्हें सब पता रहता। उसी हिसाब से वे फरमान जारी करतीं। किसी की हिम्मत न होती कि उनकी मर्जी के खिलाफ आचरण करे।

हसन जहांगीर की 'हवा...हवा...'

अपने सिर्फ एक गाने 'हवा...हवा...ए...हवा' के बल पर २५ वर्ष की उम्र में अंतर-राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर लेनेवाले पाकिस्तानी पाप-सिंगर हसन जहांगीर जब बंबई पहुंचे, तो युवा प्रशंसकों का जैसे सैलाब-सा उमड़ पड़ा। प्रसन्नता के अतिरेक में श्रोताओं ने उन पर पचास-पचास और सौ-सौ के नोटों की बरसात शुरू कर दी। मेहंदी हसन, रूना लैला तथा नाजिया हसन से भी अधिक लोकप्रियता और सम्मान बंबई के युवा दर्शकों से पाकर वे जार-जार हो रोने लगे। उन्होंने मोहम्मद रफी के चित्र पर फूल चढ़ाये और लता मंगेशकर के पांव छुए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान वे इन्हीं दोनों का करते हैं।

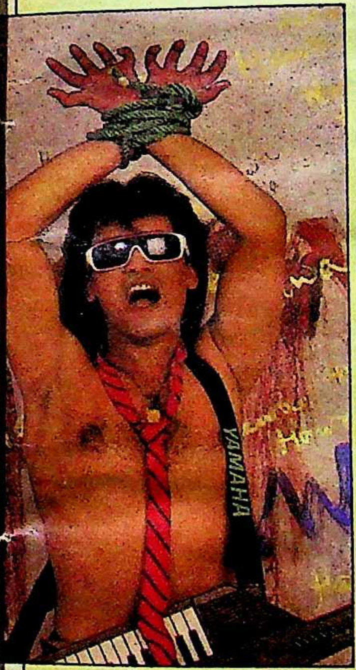

हसन जहांगीर छाया: तैयब बादशाह

हसन जहांगीर निर्माता मुन्ना रिजवी की फिल्म 'सोलह-सत्रह' (संगीत: श्रवण-नदीम) के गानों की रिकार्डिंग के लिए बंबई आये, तो उनके प्रशंसकों ने उनके ढेर सारे कार्यक्रम करा डाले। 'जलवा: ८९' समारोह में उन्हें 'बेस्ट पाप सिंगर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नर्तकी पत्नी के चलते

भरतनाट्यम प्रवीणा पत्नी हेमामालिनी ने बहुत चाहा कि धर्मेंद्र भी जीतेंद्र, अमिताभ, मिथुन और गोविंदा की तरह नृत्य में महारत हासिल करें, इसलिए उन्हें ढेर सारे फुटस्टेप्स सिखलाये, लेकिन धरम के कमर में न तो लोच थी और न ही पैरों में थिरकन। वे तो सिर्फ अपने जाट-हाथ को भांजना जानते थे, इसलिए फिल्मों में नृत्य के सीक्वेंस को हमेशा टाल जाया करते थे। लेकिन निर्माता-निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म 'ऐलान-ए-जंग' में उनसे हाथ-पैर भंजवाते-भंजवाते बाकायदे ब्रेक डांस भी करवा लिया। डिस्को सेट पर जब जयाप्रदा धर्मेंद्र के साथ ब्रेक डांस करने पहुंचीं, तो धर्मेंद्र का हुलिया देख-देखकर अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सकीं और चिंता में पड़ गयीं कि कहीं नृत्य में अनाड़ी धर्मेंद्र के साथ-साथ उनके भी हाथ-पांव न टूटें। लेकिन संगीत की धुन बजते ही धर्मेंद्र ने जब पहला स्टेप लिया, तो वे बजाय नृत्य करने के हैरत से उनका मुंह देखने लगीं, फिर निर्देशक ने जब पहले ही टेक में पूरा ब्रेक डांस ओके कर दिया, तब तो उनके विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहा। शाट ओके होते ही वे धर्मेंद्र से बेसाख्ता पूछ बैठीं—"अरे आप तो इतना अच्छा ब्रेक डांस करते हैं, फिर हेमाजी क्यों आपके पीछे पड़ी रहती हैं?" अब बेचारी हेमा क्या कहेंगी?

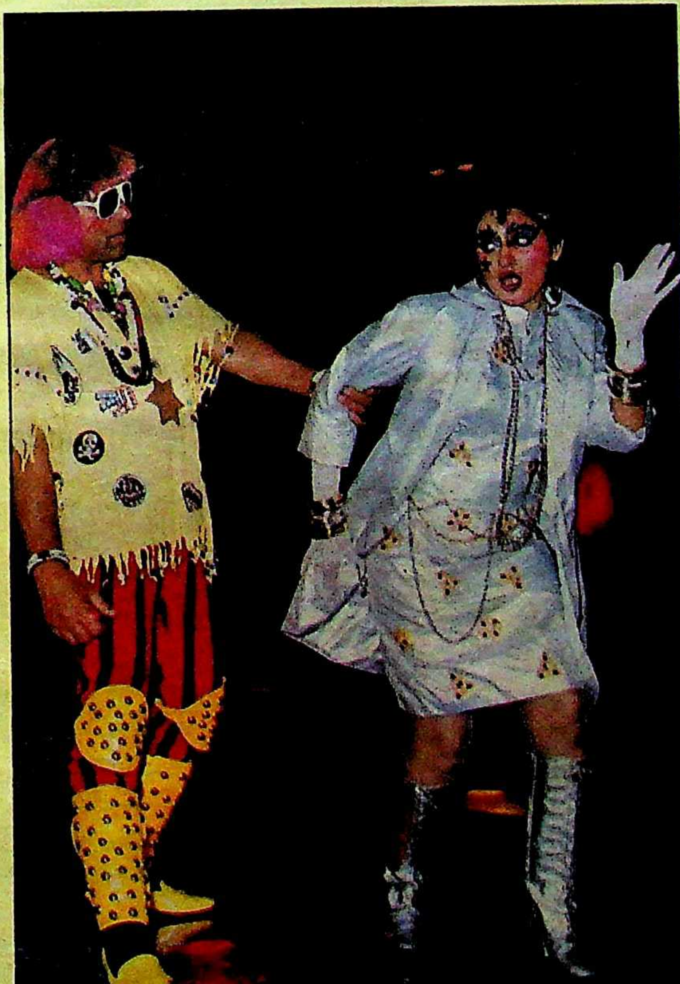

'ऐलान-ए-जंग' के ब्रेक डांस में धर्मेंद्र और जयाप्रदा

महमूद की वापसी

मराठी फिल्मों के शहंशाह-ए-कामेडियन दादा कोंडके ने जब हिंदी में 'तेरे मेरे बीच में' बनाकर अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, तब उनके 'सेंस आफ ह्यूमर' की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन जब उनकी बाद की दो फिल्में ('अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में' तथा 'आगे की सोच') बाक्स आफिस पर थोड़ी नरम गयी, तो लोग 'तेरे मेरे बीच में' की सफलता का श्रेय दादा के बजाय महमूद को देने लगे। इससे थोड़ा दुखी होकर दादा कोंडके, बंबइया फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर बंगलौर जा बसे, लेकिन महमूद के लिए उनके मन में लगाव कायम रहा। शायद इसीलिए वे महमूद को मनाकर वापस लाने उनके फार्म पर जा पहुंचे। मियां ने बहुत नानुकर की, लेकिन दादा ठहरे दादा, सो वे मियां को अपनी नयी फिल्म 'खोल दो मेरी जुबान' में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए रजामंद करा कर ही माने। —अखबारी लाल

'खोल दो मेरी जुबान' में दादा कोंडके और महमूद

सुधा चंद्रन की गुहार

एक बार सेंसर बोर्ड के एक पूर्व चेयरमैन ने मजाक-मजाक में सेंसर में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा था— 'जितनी देर में मैं बाथरूम से होकर अपनी केबिन में लौटता हूं, उतनी देर में एक फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट मेरे दफ्तर से (बिना मेरी जानकारी के) जारी हो जाता है।' अब उनके अफसर एक फिल्म को देखने-परखने में कुल कितना समय देते थे, यह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिल्म अभिनेत्री साधना और उनके पति की फिल्म 'पति परमेश्वर' उनके शिकंजे से ५८५ दिन बाद (उच्चतम न्यायालय के आदेश पर) मुक्त होकर २ जून '८६ को सिनेमा घर का मुंह देख सकी, जबकि अमिताभ बच्चन की मामूली-सी सिफारिश पर उनके दोस्त टीटो की फिल्म 'चक्रव्यूह' को २४ घंटे के भीतर पास कर दिया गया।

सेंसर बोर्ड की लालफीताशाही से तंग आकर 'पति-परमेश्वर' की नायिका सुधा चंद्रन को गुहार तक करनी पड़ी, "मैं, सुधाचंद्रन 'पति परमेश्वर' की नायिका रेखा के रूप में आपके सामने २ अक्तूबर, १९८७ को आनेवाली थी, परंतु सेंसर के प्रतिबंध के कारण दीवाली की वह रात ५८५ दिन लंबी सिद्ध हुई। जानलेवा इंतजार के इन ५८५ दिनों में मेरी सहनशीलता, मेरा पातिव्रत धर्म, दफ्तर-दर-दफ्तर, शहर-दर-शहर, छोटी से बड़ी अदालतों और अफसरशाही के कठघरों में परखा गया।...' अब सेंसर चीफ महोदय क्या कहेंगे, अपने इन अमला-उमरावों के बारे में!

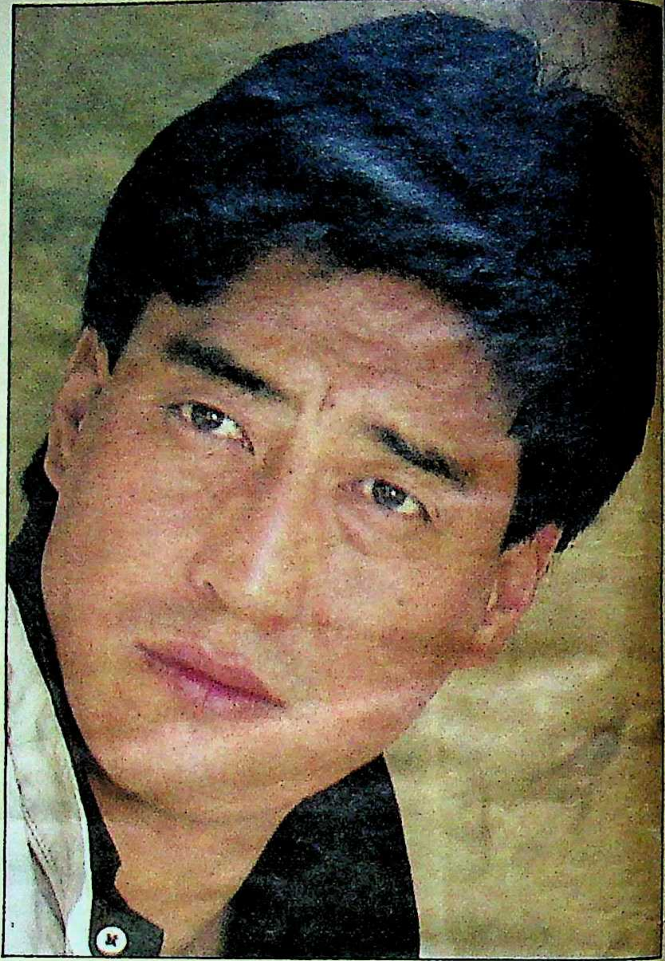

डैनी का 'सिक्किम-प्रेम'

अपने सिक्किम-प्रेम के मामले में खलनायक डैनी डेंग-जोगप्पा काफी हद तक गोरखा नेता सुभाष घीसिंग की नीति के हिमायती हैं, इसीलिए समय-समय पर वे सरकार की आलोचना करते रहते हैं। उनका मानना है कि सरकार सिक्किम के विकास के लिए कुछ भी नहीं करती है। वे अपने जन्मप्रांत सिक्किम तथा सिक्किमियों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने घर की अंत:सज्जा निखालिस सिक्किमी शैली में की है। वहां पहुंचते ही लगता है कि यह जुहू का कोई बंगला नहीं, खास सिक्किम का कोई घर है। इसी प्रेम के कारण उन्होंने अभिनेत्री किम के साथ डेढ़ दशक तक अंतरंग संबंधों के बावजूद विवाह एक सिक्किमी लड़की से ही किया।

अब अपने सिक्किम-प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने सिक्किम की संस्कृति, परंपरा और रहन-सहन के बारे में टीवी सीरियल बनाने का निर्णय किया है। इसकी सारी शूटिंग वे सिक्किम में करेंगे और वहीं के स्थानीय कलाकारों को लेंगे। इसे वे श्याम बेनेगल के 'भारत : एक खोज' से भी अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। उनका कहना है, "अगर मंडी हाउस ने रजामंदी नहीं दी, तो वे वीडियो फिल्म के रूप में इसे बनाकर देश तथा विदेशों में रिलीज कर देंगे।" अब क्योंकि वे खलनायक तथा मारधाड़ में भी प्रवीण हैं, इसलिए सिक्किम की पारंपरिक हथियार एवं रोमांचक युद्ध-कला का भी प्रदर्शन करेंगे। अब गेंद मंडी हाउस के नेट में है और आम चुनाव सामने हैं। ◆

नकुल-सहदेव के तेवर

अग्नि-सुता द्रोपदी ने पूर्व जन्म में इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर तथा धैर्यशाली पति का जो वरदान भगवान शिव से मांगा था, उसके फलस्वरूप उन्हें नकुल और सहदेव मिले। यह जरूरी नहीं कि खूबसूरती और धैर्य का तालमेल हो ही, इसलिए भगवान को उन्हें दो अलग-अलग पुरुषों के रूप में रचना पड़ा था, लेकिन ये दोनों कलियुगी 'महाभारतकार' बीआर चोपड़ा के लिए अधैर्यशाली सिद्ध हुए और उन्हें कई दिनों तक 'महाभारत' की शूटिंग रोकनी पड़ गयी।

निजी जिंदगी में भी दोनों पांडव यानी संजीव और समीर चित्रे सगे भाई हैं और डिस्को के बेहद शौकीन हैं। उनकी यह शौकीनी एक दिन उन्हें काफी महंगी पड़ गयी। द्रौपदी-चीरहरण के समय वे अपने हथियार दुर्योधन और दु:शासन के खिलाफ तो नहीं उठा सके, लेकिन एक पंचसितारा होटल के डिस्कोथेक में वे एक कन्या पार्टनर को लेकर वासवानी नामक एक शख्स से भिड़ गये, उसने बदले में बीयर की पूरी बोतल उन पर दे मारी। गयी रात तरंग में जब दोनों बंधु डिस्को से निकले, तो लोगों की सरेआम पिटाई के शिकार भी हो गये। दोनों पांडवों को अस्पताल में भरती किया गया और बंबई पुलिस को दु:शासन-दुर्योधन रूपी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए महाबलेश्वर तक जाना पड़ा। बेचारे पांडव-बंधु पिटे भी, शूटिंग भी कैंसिल हुई, चोपड़ा की डांट सुनी और ऊपर से डिस्कोथेक के मैनेजर ने यह कहते हुए उनकी १० वर्ष पुरानी सदस्यता रद्द कर दी कि 'ये नकुल-सहदेव क्या बने, महाअक्खड़ हो गये।'

'वागले की दुनिया' में अंजन श्रीवास्तव और भारती अचरेकर छाया: रथिजित घटक

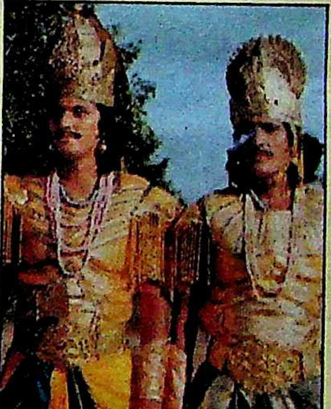

'महाभारत' के नकुल-सहदेव: समीर और संजीव

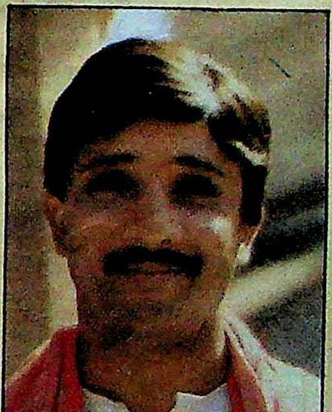

'बुनियाद' का लल्लू: राजेश पुरी

वापसियों का मौसम

मंडी हाउस में पिछले एक वर्ष से 'निर्माता पैनल' में चुनाव के लिए ३५०० से अधिक निर्माताओं की अर्जियां, लगभग इतने ही सीरियल-प्रपोजल तथा लगभग सौ पायलट दूरदर्शन अधिकारियों की हरी झंडी पाने के लिए सरकारी फाइलों की धूल चाट रहे हैं। अपनी लेटलतीफी तथा 'कार्यकुशलता' (?) के लिए बदनाम मंडी हाउस ने तीन-चार वर्षों से पड़े-पड़े सड़ रहे कई सीरियलों ('किस्सा शांति का', 'डाक्टर साहब', 'भारत की छाप', 'इंद्रधनुष', 'सिग्मा', 'मुजरिम हाजिर है', 'महानगर' आदि) को रिलीज किया, तो दर्शकों ने भी इन बसियाये सीरियलों में कोई खास रुचि नहीं दिखायी। इस पर मंडी हाउस ने लोकप्रिय सीरियलों को एक्सटेंशन देकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। पहले 'दर्पण', फिर 'मालगुडी डेज', और कथासागर' रिलीज किया, अब 'एक कहानी', 'वागले की दुनिया' और 'उड़ान' जल्दी ही रिलीज होंगे।

'वागले की दुनिया' तथा 'उड़ान' के निर्माताओं का मानना है कि उस समय इनकी लोकप्रियता का जो टेंपो बन गया था, अब उसे नये सिरे से हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की भारी मांग के बावजूद जब इसे एक्सटेंशन नहीं दिया गया, तो लोग इन्हें भूल गये। अब पुन: वही लोकप्रियता मिल पायेगी, नहीं कहा जा सकता। 'कशमकश' तथा 'रामायण' दुबारा एक्सटेंशन के बावजूद पहले जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सके। इस पर एक निर्माता ने फिकरा कसा—"लगता है, मंडी हाउस लोकप्रिय सीरियलों को एक्सटेंशन देकर उनका पोस्टमार्टम करने पर तुल गया है।"

लल्लू का नया अंदाज

'हम लोग' तथा 'बुनियाद' की अपार लोकप्रियता को फिल्मों में भुना पाने में असफल लल्लू उर्फ राजेश पुरी ने एक बूटपालिश संस्थान के लिए चार्ली चैप्लिन के गेटअप में माडलिंग की, फिर हालीवुड में चार्ली चैप्लिन पर बननेवाली फिल्म तथा ५६ एपीसोडोंवाले सीरियल में चार्ली की भूमिका निभाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन नामंजूर हो जाने पर अब वे खुद चार्ली पर एक सीरियल बनाने की सोच रहे हैं।

'बुनियाद' के बाद उन्होंने यह कहकर सीरियलों को सलाम कर लिया था कि अब जब 'हम लोग' तथा 'बुनियाद' जैसे सीरियल नहीं बन रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी प्रतिभा सीरियलों में बरबाद करूं।' लेकिन फिल्मों की असफलता ने उन्हें पुन: सीरियल का द्वार खटखटाने के लिए विवश कर दिया। वे 'किस्सा शांति का' जैसे कई सीरियलों में काम करने लगे हैं। एक वीडियो फिल्म 'एक खूबसूरत गुनाह' के लिए तो उन्होंने अपना सिर भी मुंड़ा दिया है।

अब गंजे लल्लू को दूसरे सीरियलों में काम करने के लिए भिन्न-भिन्न स्टाइल के विग बनवाने के लिए विग-मेकरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, चार्ली चैप्लिन का भी एक विग तैयार करने का आर्डर उन्होंने दे दिया है।

—दूरदर्शन लाल

Digitized ... dation Chennai and eGangotri

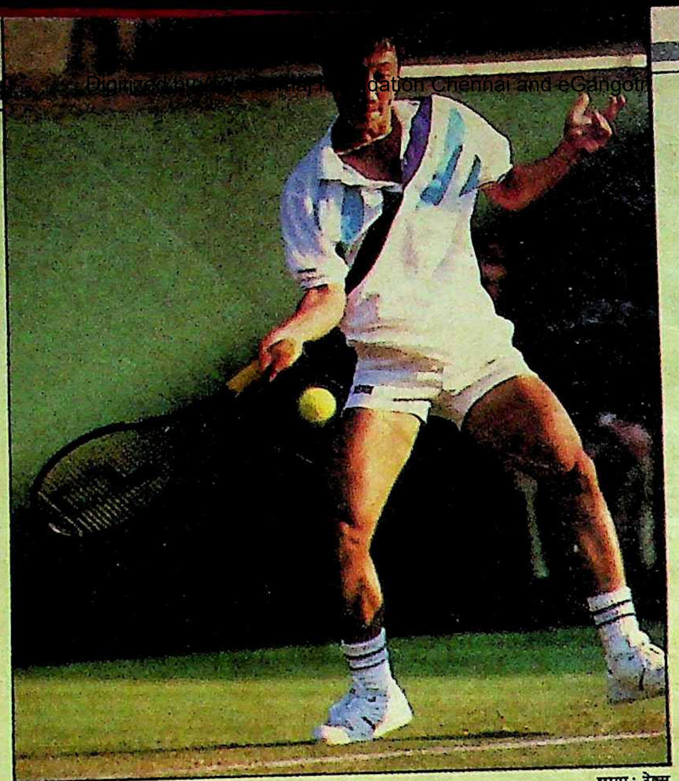

छाया : रेक्स

माइकल चांग

टेनिस का नया बादशाह

किसे पता था कि एक वर्ष पूर्व जान मैकनरो से ०-६, ३-६, १-६ से मात खानेवाला माइकल डी पेई चांग इस वर्ष इवान लेंडल, रोनाल्ड इग्नोर, आंद्रेई चेस्नोकोव और स्टीफन एडबर्ग सरीखे टेनिस बादशाहों को पराजित कर फ्रेंच ओपन टेनिस का 'नया बादशाह' बन जायेगा। इरादे पक्के हों, सही समय पर सही निर्णय लेने की सूझबूझ हो और अकूत दमखम हो, तो सफलता मिलने में समय नहीं लगता। चांग ने इसे साबित कर दिखाया है। जहां वह टेनिस में वरीयता क्रम में १९वें नंबर का प्राप्त खिलाड़ी था, वहीं अब चैंपियन होकर वह छठे स्थान पर पहुंच गया है। पहला स्थान इवान लेंडल का है और दूसरा-तीसरा स्थान बोरिस बेकर और स्टीफन एडबर्ग का है।

वैसे, इस बार की फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों के नाम ही रही। फ्रेंच ओपन टेनिस के शुरू होने के पूर्व टेनिस से नाता रखनेवालों ने सोचा भी नहीं होगा कि महिला और पुरुष-दोनों वर्गों में पांच ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीतनेवाली स्टेफी-ग्राफ और गैबरीला सबातिनी तथा विलेंडर, स्टीफन एडबर्ग और इवान लेंडल के रहते कोई तीसरा खिलाड़ी चैंपियन हो सकेगा। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होते ही जब परिणाम सामने आने लगे, तो सभी हतप्रभ रह गये। एक-एक करके सभी दिग्गज खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गये और उनकी जगह सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों ने ले ली।

स्पेन की १७ वर्ष ५ माह की अरांतजा सांचेज ने महिलाओं के फाइनल में स्टेफीग्राफ को ७-६, ३-६, ६-४ से हराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया, तो पुरुषों के फाइनल में अमरीका के माइकल चांग ने स्टीफन एडबर्ग को ६-१, ३-६, ४-६, ६-७, ६-२ से हराकर रिकार्ड कायम किया। जहां सांचेज ने यह खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की विजेता होने का गौरव हासिल किया, वहीं माइकल चांग (१७ वर्ष साढ़े तीन माह) भी इस गौरव का भागीदार बना। सांचेज के पहले १९८६ में स्टेफीग्राफ ने १७ वर्ष ११ मास की उम्र में यह खिताब जीतकर रिकार्ड कायम किया था। माइकल चांग तो सांचेज से भी डेढ़ मास छोटा है। माइकल से पूर्व १९८२ में सबसे कम उम्र का चैंपियन विलेंडर (१७ वर्ष ९ माह) बना था और इसके बाद १९८५ में इस रिकार्ड को बोरिस बेकर (१७ वर्ष ७ माह व ७ दिन) ने तोड़ा था।

आंकड़े बताते हैं कि चांग टेनिस इतिहास के किसी भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का सबसे कम उम्र का विजेता है। आंकड़ा विशेषज्ञों का अनुमान था कि राउनी हीथ ने १७ वर्ष की उम्र में १९०५ में आस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, पर यह अनुमान तब धरा रह गया, जब आंकड़ा विशेषज्ञों ने घंटों की मेहनत के बाद राउनी हीथ की जन्म तिथि ढूंढ़ निकाली। राउनी हीथ माइकल चांग से उम्र में बड़े निकले और अब तो टेनिस विशेषज्ञों को नहीं लगता कि कोई चांग के रिकार्ड को तोड़ पायेगा।

गत फरवरी में जब परागुने के विरुद्ध डेविस कप के लिए अमरीकी टीम घोषित हुई, तो उसमें चांग का नाम भी शामिल था और यह नाम टीम में होना टेनिस के जानकारों के लिए एकदम अप्रत्याशित था।

माइकल चांग की जीत से अमरीकी टेनिस को नया जीवन मिला है। १९५५ में ट्रानी ट्रिबट के खिताब जीतने के बाद से कोई अमरीकी खिलाड़ी फ्रेंच ओपन में चैंपियन नहीं बन सका था। इस प्रकार ३४ वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद किसी अमरीकी खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन खिताब जीतने का गौरव हासिल किया है।

पांच फुट, आठ इंच लंबा और ६१ किलोग्राम वजन का माइकल चांग मूलत: चीन का है। उसके पिता जो चांग और माता बेट्टी ताइवान से अमरीका आकर बस गये हैं। दोनों पेशे से रिसर्च केमिस्ट हैं। दायें हाथ से टेनिस खेलनेवाला चांग मितभाषी और निरभिमानी है। उसके पिता ही चांग के एक तरह से मुख्य प्रशिक्षक हैं और उसकी मां उसके साथ यात्रा कर उसकी समस्याओं को सुलझाती हैं तथा उसके रहन-सहन और खानपान का खयाल रखती हैं।

माइकल चांग ईसा मसीह का परम भक्त है। फ्रेंच ओपन जीतने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में चांग ने कहा कि दरअसल बधाई तो प्रभु ईसा मसीह को दी जानी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी मुझे मिलता है, उसका श्रेय मैं उन्हें ही देता हूं। प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी गहरी आस्था को वह प्रतियोगिता में अपनी हर विजय के बाद व्यक्त करता रहा। चांग की प्रेरणा कुछ भी रही हो, लेकिन उसके प्रशिक्षक जोंस हिग्युएरस को उसके जीतने की पूरी उम्मीद थी। जोंस मानते हैं कि चांग के पास एक चैंपियन का दिमाग है। ३४ वर्ष पहले अमरीका के लिए फ्रेंच ओपन खिताब जीतनेवाले ट्रिबट का मानना है कि ऐसा खिलाड़ी मुश्किल से पैदा होता है। चांग ने २, ९१, ७५२ डालर का खिताबी पुरस्कार जीतने के बाद विजय के उल्लास में सिर पर मुक्का मारते हुए कहा कि 'इस बारे में सोच पाना भी मेरे लिए कठिन था। मुझे जीत की कल्पना भी नहीं थी। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण खिताब है। यह मेरी महान कामयाबी है।'

चांग अपने टेनिस कैरियर के लिए वर्ष १९८८ को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। १९८८ में उसने अपनी कमियों को जाना और बहुत कुछ सीखकर उन्हें दूर किया। वह स्वीकार करता है कि १९८८ में इवान लेंडल और आंद्रे अगाशी ने उसे बहुत से गुर सिखाये।

माइकल चांग का असली सपना फ्रेंच ओपन खिताब ही जीतना नहीं था। वह तो अमरीका को विंबलडन और डेविस कप का खिताब भी दिलवाना चाहता है। चांग कहता है, "मैं नंबर एक बनना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अमरीका के लिए डेविस कप जीतना चाहता हूं।"

माइकल चांग का यह सपना साकार होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। पर लंदन में आयोजित राउंड रोबिन कांटीनेंटल ग्रास कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता में १४ और १५ जून को जौन क्रीक और केली एवरंडेन के हाथों चांग की पराजय ने उसके भविष्य पर प्रश्नचिह्न अवश्य लगा दिया है। इसके बावजूद माइकल चांग और उसके पिता १९९० का डेविस कप अपनी झोली में देख रहे हैं।

—दिनेश दीनू

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

ह में
हूं तो
ानी
मुझे
हैं ही
प्रति
वह
य के
की
उसके
उसके
जोंस
एक
पहले
बताव
है कि
होता
डालर-
के बाद
मुक्का
में सोच
। मुझे
ा। यह-
है। यह

यर के
हत्वपूर्ण
अपनी
त कुछ
। वह
८८ में
ाशी ने

असली
जीतना
का को
रूप का
हता है।
क बनना
पहले
जीतना

ह सपना
नहीं जा
ायोजित
ास कोर्ट
और १५
र केली
राजय ने
ले अवश्य
बावजूद
के पिता
नी झोली
दिनेश दीनू

हुत हाउस,

HarSafar Main HumSafar...
कुमार
पान मसाला
KUMAR
PAN MASALA
कुमार
पान मसाला
कुमार
पान मसाला
जर्दा मिक्स

KUMAR®
PAN MASALA

Mfd. by— Kumar Chemicals, Kanpur-208 001
PHONE No. : 52303, 52305

Statutory Warning : Chewing tobacco is injurious to health

NOTE : DEALERSHIP ENQUIRIES SOLICITED FOR UNREPRESENTED AREAS.

28/11/86

जो सुरक्षा रेमण्ड सीमेंट से मिले वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले.

इसलिए चाहे आपका अपना घर हो या दफ़्तर या फिर कोई अन्य निर्माण कार्य, भरोसा कीजिए केवल रेमण्ड सीमेंट पर. क्योंकि रेमण्ड सीमेंट की तरह ही ठोस हैं इसके फ़ायदे : उत्तम दबाव शक्ति (कम्प्रैसिव स्ट्रैंथ), जमाव का बढ़िया मानक, मज़बूत पैकिंग.

जी हां, रेमण्ड सीमेंट को बरसात, धूप और समय जैसी कुदरत की फ़ौलादी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है.

याद रखिए, रेमण्ड सीमेंट के कण-कण में भरी है सर्वोत्तम सुरक्षा और सर्वोत्तम शक्ति.

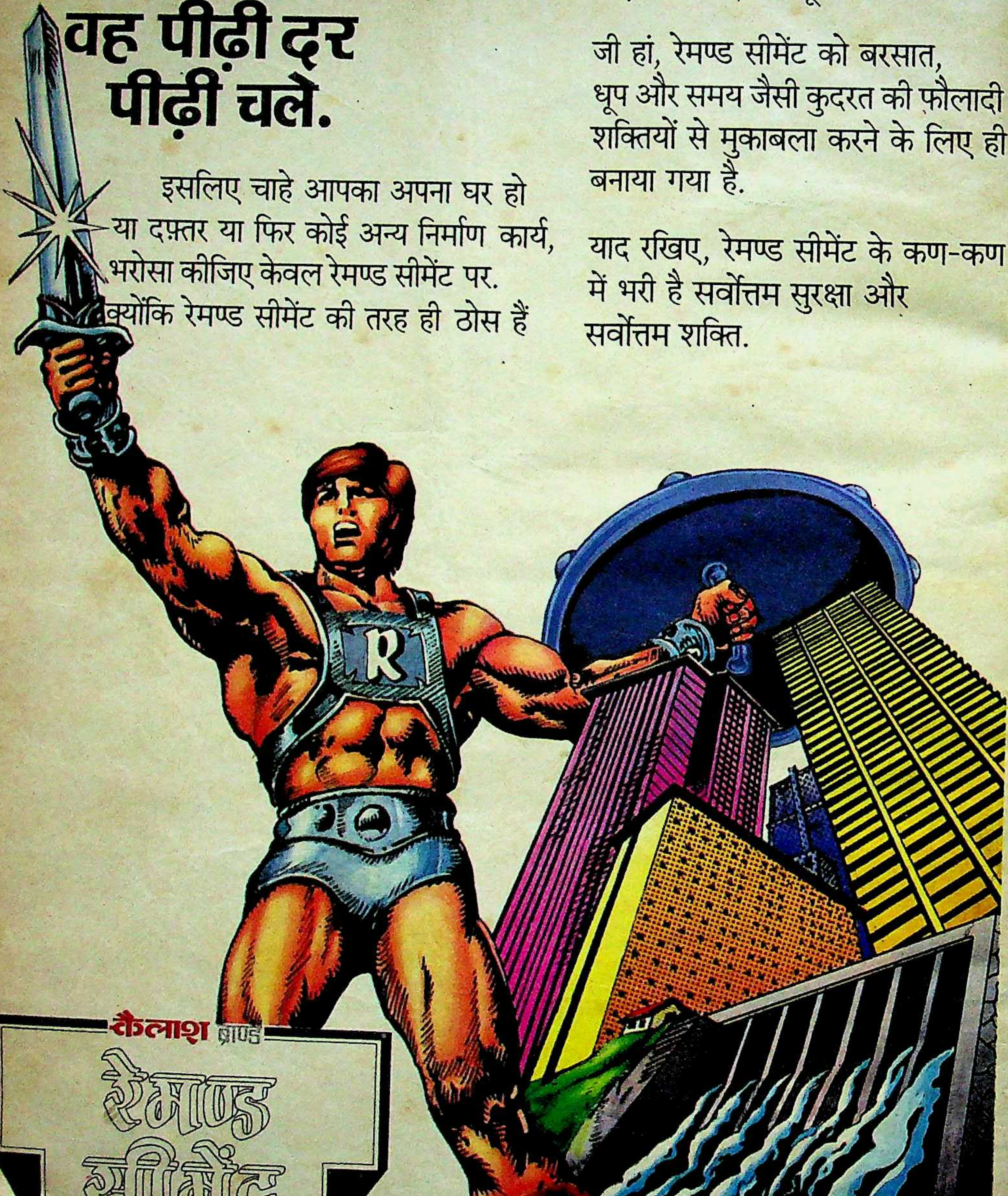

कैलाश ब्राण्ड

रेमण्ड सीमेंट

१०० साल वाला सीमेंट

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका
माया
वर्ष ६०, अंक १४
३१ जुलाई, १९८९

संस्थापक
स्व॰ श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा॰ मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

॰प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ॰दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल-१७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं॰ ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५ जयपुर कार्यालय: ए-२० शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर-४ फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

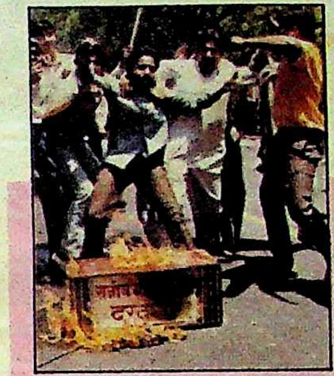

२९

आवरण कथा

सरकार-नियंत्रित सूचना माध्यमों—टीवी-रेडियो—की विश्वसनीयता पर उंगली तो पहले भी उठायी जाती रही है, लेकिन विपक्ष पर चुनावी हमला करने के लिए उनके दुरुपयोग को लेकर कुछ समय से काफी हंगामा मचा हुआ है। २५-२६ जून को तो विपक्ष ने इस मुद्दे के सिलसिले में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करके गिरफ्तारियां भी दी हैं। क्या वास्तव में कांग्रेस ने इन सूचना माध्यमों को अपने चुनाव-प्रचार और विपक्ष के चरित्रहनन का जरिया बना लिया है?

विशेष रिपोर्ट

दुबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद मोतीलाल वोरा ने ऐसी कौन सी कार्यशैली अपनायी कि वे दब्बू से दबंग कहे जाने लगे हैं? १७

बिहार

'छोटे साहब' के रूप में ख्यात मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के सौ दिनों के कार्यकाल की खूबियां और खामियां ७८

असम

बोडो समस्या और पार्टी में फूट के साथ क्या मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत चावल घोटाले में भी फंस गये हैं? यह चावल घोटाला क्या है? २६

तमिलनाडु

विधानसभा चुनाव में द्रमुक द्वारा बाजी मार लेने के बाद अब तमिल राजनीति किस व्यामोह में फंसी हुई है? ६२

उत्तर प्रदेश

राजनीति के अपराधीकरण ने क्या असामाजिकता और सियासत की विभाजक रेखा को समाप्त कर दिया है? २२

उड़ीसा

जेबी पटनायक कांग्रेस के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नौ वर्ष से लगातार अपने पद पर जमे हैं। उनके लंबे कार्यकाल का जायजा ७१

दिल्ली दरबार: चलो नारे लगाओ! १०
फोटोफीचर १३
केके तिवारी से विशेष साक्षात्कार ४०
गुजरात: किसान आंदोलन से मुख्यमंत्री चौधरी सांसत में ६०
मध्यप्रदेश: वीर विक्रम सिंह: सामंती आतंक का लोमहर्षक अध्याय ६५
राजस्थान: अजमेर: गरीब नवाज के घर में कलह का राज ७३
बिहार: आजाद की पदयात्राओं का मतलब ७६
दुनिया: ब्रिटेन: राजघराने में प्रेम-प्रसंगों का भंडाफोड़ ८२
पड़ोस: श्रीलंका: शांति सेना से अशांति का खतरा ८५
अर्थतंत्र ९०
स्त्री: बांधवी के बजाय बंधुआ बनाने का रिवाज ९२
बेढब ९४
दूरदर्शन: 'मुजरिम हाजिर': सच से साक्षात्कार ९५

आवरण पारदर्शी
सुनील सक्सेना
(टीवी विरोधी प्रदर्शन)
गिरीश श्रीवास्तव
(केके तिवारी)

माया
कांग्रेस के मुकाबले
विपक्ष कितने पानी में?

कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष कितने पानी में

१५ जुलाई की 'माया' मिली। आवरण कथा 'कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष कितने पानी में' पढ़ी। 'माया' ने सही ही लिखा है कि जहा विपक्ष अभी एकता का प्रयास कर रहा है, वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार करने और चुनाव प्रसाद बांटने की पहल में बाजी मार चुकी है। क्योंकि राजीव गांधी पूरे देश के ताबड़तोड़ दौरे, विपक्ष की खिचाई और आलोचना में लगे हैं, जबकि विपक्ष की आलोचनाओं का कोई प्रभाव जनमानस पर नहीं दिख रहा है। माना कि विपक्ष ने आरिफ मोहम्मद खान के संयोजकत्व में सात सदस्यीय तदर्थ समिति बना दी है, चंद्रशेखर को भी एक पद देकर खुश कर दिया गया है, लेकिन असल समस्या तो दिल मिलने की है। ऊपर से एकता दिखाने और भीतर से टांग खिचाई में लगे रहनेवाला विपक्ष कांग्रेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह ठीक है कि जद अकेला नहीं है, लेकिन सरकार में रहने के कारण कांग्रेस-इ के पास तंत्र और अमले का जो जोर है, उसके काट के लिए विपक्ष को कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कि 'काम के अधिकार' को लेकर विपक्ष जो हस्ताक्षर अभियान चलानेवाला है और १५ अगस्त, १९८९ को 'पूर्ण रोजगार' दिवस के रूप में माननेवाला है, उससे जनता प्रभावित हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से निबटने के लिए काफी दम-खम की जरूरत है।—**किट्टनपणिक्कर, तोड़पुडा केरल**

कांग्रेस का चुनावी नुस्खा

३० जून '८९ की 'माया' में 'कांग्रेस का चुनावी नुस्खा' पढ़ा। कथा बेहद सटीक लगी। राजीव सरकार द्वारा 'जवाहर रोजगार योजना' और 'पंचायती राज' चुनावी हथकंडा नहीं तो और क्या है? स्व० इंदिरा गांधी ने १९७१ में 'गरीबी हटाओ', १९८० में 'काम करने वाली सरकार लाओ', १९८४ में 'देश की एकता-अखंडता' के नारे लगाकर बहुमत प्राप्त किया था और अब राजीव गांधी 'जवाहर रोजगार योजना' और 'पंचायती राज' के सहारे पार लगना चाहते हैं, पर भारत की जनता अब काफी जागरूक हो गयी है। उसे आज बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।—**संतोष कुमार सिंह, सब्जी पट्टी झरिया, धनबाद, बिहार**

मात्र कांग्रेस की 'बी' टीम नहीं

'माया' ३० जून के अंक में रंजना कक्कड़ ने प्रगतिशील मोर्चा को कांग्रेस की 'बी' टीम सिद्ध करने के प्रमाण दिये हैं। इस तरह तो 'जद' को इससे भी ठोस प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सकता है कि वह मात्र कांग्रेस की सत्यप्रतिलिपि है। यदि जद का वास्तविक विश्लेषण किया जाये, तो यह मात्र ढाई जातियों का (पूरे 'अजगर' का भी नहीं) जमावड़ा मात्र है। एक हैं वीपी सिंह, चंद्रशेखर आदि (राजपूत) दूसरे हैं देवीलाल, अजीत सिंह आदि (जाट) तथा आधे में कुछ अहीर-मुलायम सिंह, शरद यादव आदि। इन 'अजगरों' से अन्य जातियां भय खा रही हैं। उधर जपा में व्यापक छवि वाले नेता हैं। इंदुभाई पटेल (अध्यक्ष) व देवगौड़ा जनाधारवाले हैं, तो सैयद शहाबुद्दीन मुसलमानों व रामधन हरिजनों का ठोस आधार रखते हैं। यह भी सत्य है कि चंद्रशेखर और अजीत सिंह जैसे ग्रहों के टूटकर प्रगतिशील मोर्चा की तरफ आने की ही अधिक संभावना है। 'जद' के संभावित बिखराव का लाभ प्रगतिशील मोर्चा को ही मिलेगा।—**जयकरण सिंह गुर्जर, मेरठ उप्र**

ठक्कर की भविष्यवाणी

३० जून की 'माया' में सुखलाल ठक्कर की भविष्यवाणियां पढ़कर बड़ा आनंद आया। भगवान बुद्ध की कुंडली के अनुसार उन्हें या तो चक्रवर्ती सम्राट होना था या महान तपस्वी। भगवान तपस्वी हुए। राजीवजी की कुंडली भगवान बुद्ध की कुंडली से प्रबल है, क्योंकि बुद्ध तो तपस्वी ही हो सके। राजीवजी चक्रवर्ती सम्राट तो हैं ही—यदि तपस्वी भी हो जायें, तो क्या कहना! राजनीति में तथा देश का जो हाल उन्होंने किया है, उसको देखकर लाखों भारतीय नाक रगड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु भारत को एक और गौतम बुद्ध शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करे। यह अवतारों का देश है—सत्रहवां अवतार भी यहां चलेगा।

एक और आवश्यक सूचना देना चाहता हू। वह यह कि श्री ठक्कर के ग्रह भी बहुत उच्च हैं। यदि वे ऐसी ही भविष्यवाणियां सर्वश्री बूटा सिंह, 'कक्काजी कहिन', तिवारी, सीताराम केसरी, कल्पनाथ राय, अमिताभ बच्चन, सतीश शर्मा इत्यादि के बारे में भी कर डालें, तो निश्चय ही कुछ अन्य सरकारी ज्योतिषियों, ब्रह्मचारियों तथा स्वामियों की तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा कूटनीति में महान सफलता तथा ख्याति प्राप्त करेंगे। कम-से-कम भारत में किसी राज्य के राज्यपाल तो बन ही जायेंगे। —**मोहन चंद्र सिंह, मिरचई लेन, पटना**

आरक्षण का असली चेहरा

३० जून की 'माया' में 'आरक्षण का असली चेहरा' पढ़ा। मेरे विचार से आरक्षण के नाम पर चयन की पवित्रता को ही आहत करनेवाली प्रक्रिया ने कितने ही प्रतिभा-पुष्पों को समय से पहले मुरझाने को मजबूर कर दिया है। जाति प्रथा का उन्मूलन करने का स्वांग रचनेवाले इन्हीं राजनेताओं ने जातिगत आरक्षण द्वारा समाज में विभाजन रेखाएं खींच दी हैं। आर्थिक दृष्टि से विपन्न हर व्यक्ति को सहायता देना तो न्यायोचित है, मगर सिर्फ जातिगत आधार पर सीट की सुरक्षा करना समाज को खंडित करने के यज्ञ में आहुति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

आजादी के चालीस वर्षों बाद भी यदि सरकार को 'हम सब एक हैं' के नारे लगाने पड़ें, तो यह साबित होता है कि निश्चय ही हम सब एक नहीं हैं। कहीं भीतर कोई गहरा घाव है, जिसे इस लुभावने नारे से छिपाने का फूहड़ प्रयास किया जा रहा है। निश्चय ही इसकी जिम्मेदार है, सरकार की वह संकीर्ण आरक्षण नीति, जिसमें जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है।—**रवि प्रकाश जैन, मोहन बाड़ी, जयपुर**

देह से दौलत तक

'माया' (३० जून '८९) में पामेला की रोमांचक डायरी 'देह से दौलत तक' शीर्षक के अंतर्गत पढ़ी। सचमुच पामेला ने यह डायरी लिखकर साबित कर दिया है कि वह पैसे के खातिर किसी के साथ रात गुजार सकती है अर्थात महंगी काल गर्ल्स के सभी गुण उसमें मौजूद हैं। दूसरी ओर, पामेला के साथ रात गुजारने वालों में मशहूर नेता, पत्रकार, ऋषि-योगी भी शामिल थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग तो महज 'कुछ क्षणों' के सुख के लिए किसी अजनबी के साथ रात गुजार लेते हैं, किंतु छोड़ जाते हैं देश—जनता को महत्वपूर्ण जानकारी सहित अपनी गुप्त कमजोरियां जो कभी भी किसी क्षण हानिकारक सौदे का रूप ले लेती हैं।—**शैलेंद्र सिंह तरकर, सनहौली, खगड़िया, बिहार**

स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी!

'माया' (३० जून '८९) में 'स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी' पढ़कर मन को बहुत आघात लगा। सिर्फ चार सौ रुपए पेंशन एवं कुछ सुविधाओं के लिए हमारे माननीय विधायक श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने जो कर्म किया, उससे हमारे देश को एवं देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो जानेवालों का सिर शायद शर्म से झुक गया होगा। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एवं अन्य वीर सपूतों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो कष्ट सहे एवं कुर्बानियां दीं, उनकी आत्मा हनुमान प्रसाद कुरील के स्वतंत्रता सेनानी बनने पर सोचने को मजबूर हो गयी होंगी कि नाहक उन्होंने ऐसा किया एवं जीवन दान दिया, कुरील की तरह ठाठ से जीकर भी स्वतंत्रता सेनानी कहलवा सकते थे। खोट तो सरकारी तंत्र का है, जिसने इस बाबत कोई जांच नहीं की। उनको प्रमाण पत्र और पेंशन देने की व्यवस्था कर दी। धन्य है, हमारी सरकारी मशीनरी। जहां तक कांग्रेस में धोखेबाजों और जालसाजों के संरक्षण का प्रश्न है, तो यह कोई अजूबी बातें नहीं है, क्योंकि चुनाव एक जंग है और जंग में सब जायज है। इसमें सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। क्या कांग्रेस, क्या विपक्ष धन एवं

पद की लोलुपता जब तक बनी रहेगी, सामाजिक मूल्यों की परिभाषा मिल पाना असंभव है।—**अरुण भट्टाचार्य, द्वारा एवरी इंडिया लि०, स्वरूप नगर, कानपुर**

नियम-कायदों और अधिकारों का युद्ध

'माया' के ताजे अंक (३० जून) में ओम सैनी द्वारा लिखा गया मंत्री-नौकरशाह विवाद पर लेख अत्यंत प्रभावशाली व युक्तिसंगत लगा। राजस्थान में खानों के आवंटन को लेकर आपके द्वारा उठाया गया यह प्रश्न कि मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच जो जंग छिड़ी है, उसमें वर्चस्व का सवाल है या स्वार्थ का? आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। जब देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्वार्थ से कहीं अधिक वर्चस्व का सवाल ज्यादा अहम है। नौकरशाही दिनोदिन प्रशासन पर हावी होती जा रही है। जन-प्रतिनिधि, जिसकी प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अपने आपको असहाय व अक्षम महसूस करने लगा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। श्री डीआर मेहता—लक्ष्मणसिंह प्रकरण को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। लक्ष्मणसिंह पर लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने खानों के आवंटन में अपने साले को खान दिलवाने के लिए हस्तक्षेप किया, बेबुनियाद-सा लगता है। जबकि डीआर मेहता ने जैन समुदाय के लोगों का आवंटन में खुले आम पक्ष लिया जो कि 'मेरिट' में नहीं आते थे। इसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी व उन्होंने नौकरशाही के वर्चस्व के लिए सभी हथकंडे अपनाये। विवाद में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री का साथ देकर व मेहता का स्थानांतरण कर प्रजातंत्र पर नौकरशाही को हावी होने से बचा लिया। भविष्य में यदि अधिकारीगण मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करने लगेंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ढह जायेगी।—**कमल कुमार शर्मा, १६, रामनगर, हवा सड़क, सोडाला, जयपुर**

बिना वीर बहादुर सिंह के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस

'माया' का ३० जून '८६ का अंक पढ़ा। 'माया' ने उक्त विषय पर जो लेख लिखा है, वह अक्षरशः सत्य है। स्व० वीरबहादुर सिंह सचमुच कांग्रेस के एक सच्चे तथा वफादार प्रहरी थे। उन्होंने अपने समर्थकों की एक इतनी अच्छी टीम तैयार कर ली थी कि अन्य नेता घबराने लगे थे। वीर बहादुर सिंह बिजली के उस तार के समान थे, जिसको छेड़ने पर अपने तथा विरोधियों दोनों को झटका लगता था। वीर बहादुर सिंह के निधन से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो परेशानी उठानी पड़ेगी, उसका कुछ महीनों में ही पता लग जायेगा। इसलिए, तिवारी सरकार को हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए। यह चर्चा है कि पूर्वी उप्र के बहुचर्चित तथा वीर बहादुर के एक कट्टर विरोधी, निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल होनेवाले हैं। विश्वास है कि राजीव गांधी ऐसे लोगों को शामिल करके कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है, तो वीर बहादुर के समर्थकों पर 'जले पर नमक छिड़कना' होगा।—**एचके यादव, रेसकोर्स, नयी दिल्ली**

निवेदन

आपने 'माया' पत्रिका के १५ जून, १९८९ के अंक में 'नकली दवाओं का पनपता कारोबार' लेख राजस्थान राज्य के बारे में प्रकाशित किया है (पृष्ठ संख्या ४७)। इस क्रम में हमें कहना है कि इस लेख में जो आपने राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर का चित्र अंकित कर लिखा है 'बेकार-राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला' यह अनुचित व अवांछित है। यह उल्लेखनीय है कि लेखक ने बिना जानकारी प्राप्त किये ही इस चित्र को अंकित किया है, जबकि वास्तव में इस प्रयोगशाला में औषधि विश्लेषण कार्य नहीं किया जाता है। अतः इसका अंकन किया जाना अवांछित है।—**आर गुप्ता, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर**

स्पष्टीकरण

'माया' के मार्च, १९८३ अंक के पृष्ठ १४ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में जो टीका-टिप्पणी की गयी है, वह श्री सुब्रहमण्यम स्वामी की अपनी है, 'माया' की नहीं। 'माया' श्री वाजपेयी जैसे वरिष्ठ और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता का सम्मान करती है। यदि श्री स्वामी की टिप्पणियों के प्रकाशन से किसी के सम्मान और भावनाओं को चोट पहुंची है, तो इसका हमें खेद है।

—संपादक

◆ खयालात

केसरिया और लाल झंडे साथ-साथ लहरा रहे हैं? सत्ता का सुख भोगने के लिए?—**राजीव गांधी, इंदौर में।**

प्रधानमंत्री या तो अखबार पढ़ते ही नहीं, या फिर उन्होंने झूठ बोलते रहना ही तय कर लिया है।—**वीपी सिंह, नयी दिल्ली में।**

समूचे आतंकवाद के पीछे बूटा सिंह हैं।—**देवीलाल, श्रीनगर में।**

राजीव गांधी देश को न कभी रास आये, न आयेंगे।—**रामकृष्ण हेगड़े, दिल्ली में।**

सरकार का यह मानना कि वीपी सिंह से शांति-भंग का अंदेशा है, विशुद्ध झूठ के सिवा कुछ नहीं।—**रामधन (जनमोर्चा नेता), नयी दिल्ली में।**

अगर एक पायलट एक राष्ट्र का, एक बस चालक एक राज्य का संचालन कर सकता है, तो एक सिविल इंजीनियर के स्थान पर एक मैकेनिकल इंजीनियर काम क्यों नहीं कर सकता?—**आईएएस एलएम, भोपाल में।**

राजीव गांधी

उप्र सरकार की आरक्षण—घोषणा पिछड़े वर्गों के साथ धोखाधड़ी और चुनावी बहलावे के सिवा कुछ नहीं है।—**चंद्रजीत यादव, लखनऊ में।**

तारिक अनवर (सांसद) कांग्रेस-इ के कैदी हैं।—**राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन के संयोजक सैयद शहाबुद्दीन, नयी दिल्ली में।**

गीशा मित्सुको नाकानिशी

मुझे कुरसी से हटाने में शरद पवार विरोधी लीडरों का ब्रह्मास्त्र बन गये थे, अब वे भी स्कैंडल में फंस गये हैं, मैं उनका ऋण उन्हीं की मुद्रा में चुकाऊंगा।—**एआर अंतुले, 'टेलीग्राफ' में।**

मैं तो गीता के अनुसार चलता हूं, मैं वस्तुओं को उसी रूप में देखता-समझता हूं, जैसी वे होती हैं।—**ज्योति बसु, कलकत्ता में।**

मेरे पास ऐसी खबरें, ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वे (जनरल जिया) कितने इस्लाम विरोधी थे।—**बेनजीर भुट्टो, सऊदी गजट में।**

मेरे लिए यह एकदम नागवार है कि अबला की भावनाओं को चोट पहुंचानेवाला संगदिल उनो जैसा शख्स जापान का प्रधानमंत्री हो।—**४० वर्षीया गीशा मित्सुको नाकानिशी, टोकियो में।**

भारतीय शांति सेना को हटाने के लिए राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास ने जो तरीका अपनाया है, उससे उनका भी विनाश हो सकता है।—**बौद्ध भिक्षु सोबित थेरा, कोलंबो में।**

हमारी पार्टी सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ही हिंदू धर्म का सार-तत्व है।—**शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, बंबई में।**

देश

१६ जून : प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा कांग्रेस के राज्याध्यक्षों और महासचिवों को अगले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार न बनाने का फैसला। असम के सांसद गोकुल सैकिया कार की चोरी के आरोप में गिरफ्तार।

१७ जून : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त।

१८ जून : राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में ३७५ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। मशहूर उर्दू लेखक, कवि व पत्रकार १०० वर्षीय जफर हुसैन का लखनऊ में निधन।

१९ जून : मिजोरम मंत्रिमंडल का विस्तार, तीन और मंत्री शामिल। बंबई हाईकोर्ट द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक 'संडे आब्जर्वर' के संपादक राहुल सिंह की गिरफ्तारी पर रोक।

२० जून : बिहार प्रदेश कांग्रेस-इ के अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र राज्यस्तरीय २० सूत्री कार्यक्रम समन्वय समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु में राज्यसभा की रिक्त छह सीटों के लिए चुनाव १३ जुलाई को कराने की घोषणा। भारत का इनसेट-१डी प्रक्षेपण के समय क्षतिग्रस्त।

२१ जून : कश्मीर की गुलाम मुहम्मद सोफी के नेतृत्ववाली नेशनल कांफ्रेंस का कांग्रेस-इ में विलय।

२२ जून : मुख्य चुनाव आयुक्त आरबीएस पेरिशास्त्री द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव एक साथ दिसंबर में कराने की घोषणा।

२३ जून : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद केडी सुलतानपुरी का अपने पद से इस्तीफा।

२४ जून : शेतकरी संगठन के नेता शरद जोशी, भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत संयुक्त रूप से चुनावी रणनीति बनाने पर सहमत। पेरुराम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नये अध्यक्ष नियुक्त। उप्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में १५ फीसदी आरक्षण।

२५ जून : पंजाब में फरीदकोट जिले के मोगा कस्बे में आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर अंधाधुंध गोली एवं बमवर्षा, २९ व्यक्ति मृत एवं २२ घायल, मोगा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर कब्जा करने के आरोप में हैदराबाद में १४०० से अधिक भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार।

२६ जून : पूरे देश में विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा दूरदर्शन के सरकारीकरण के विरुद्ध प्रदर्शन, पटना तथा विजयवाड़ा में पुलिस की लाठी से ६२ प्रदर्शनकारी घायल, दिल्ली में दस हजार कार्यकर्ताओं के साथ जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह, कर्नाटक में हजारों कार्यकर्ताओं सहित जनता दल उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े गिरफ्तार।

२७ जून : मोगा के नरसंहार के विरोध में देशव्यापी बंद, केरल में हिंसा भड़की।

२८ जून : गुजरात के कानून और पर्यटन मंत्री ५८ वर्षीय बाबू भाई सुपारीवाला का निधन। विपक्षी दलों द्वारा आयोजित बंद के सिलसिले में पटना पहुचने पर वीपी सिंह ५०० कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार।

२९ जून प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा विश्वविद्यालय आयोग की पूर्वअध्यक्ष ७० वर्षीया डा० श्रीमती माधुरी शाह का निधन।

३० जून स अखिल भारतीय सिख छात्र महासंघ के आह्वान पर पंजाब बंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन १४, १५ नवंबर को इलाहाबाद में होने की घोषणा।

जगन्नाथ मिश्र

महेंद्र सिंह टिकैत

आंद्रेयास पापेंद्रु

चियांग चेमिन

विदेश

१६ जून : ब्रिटेन में हाउस आफ़ कामंस की दो सीटों के चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी विजयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन ईरानियों को सलमान रुशदी को मारने की धमकी देने के आरोप में २७ जून तक ब्रिटेन छोड़ने का आदेश।

१७ जून : पेइचिंग मे एक महिला सहित आठ 'प्रतिक्रांतिकारियों' को फांसी।

१८ जून : श्रीलंका सरकार द्वारा भारतीय शांति सेना की उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाने का विचार।

१९ जून : यूनान के चुनावों में पापेंद्रु की पेनहेलैनिक सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी (पसोके) पराजित। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत, जापान और ब्राजील के खिलाफ अमरीका के 'सुपर ३०१' के इस्तेमाल की निंदा।

२० जून : श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास द्वारा बढ़ती हुई नागरिक अशांति और सरकार विरोधी हड़तालों के कारण राज्य में पुनः आपातस्थिति की घोषणा।

२१ जून : चीनी अधिकारियों द्वारा विशाल जनसमूह के समक्ष तीन और 'प्रतिक्रांतिकारियों' की गोली मार कर हत्या। ब्रिटेन में वेतनवृद्धि को लेकर रेल एवं बस कर्मचारियों की २४ घटे की हड़ताल।

२२ जून : लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (मुक्ति चीते) द्वारा भारतीय शांति सेना से युद्धविराम की पेशकश। चीन में ७ और 'प्रतिक्रांतिकारियों' को फांसी।

२३ जून : अंगोला के राष्ट्रपति एडुआर्डो डास सैंतोस तथा अमरीका समर्थित दल 'यूनीटा' के नेता औनास साविबी में समझौता, १४ वर्षों से जारी गृहयुद्ध समाप्त करने की घोषणा, 'यूनीटा' के ७०० सदस्यों की रिहाई के आदेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास द्वारा २९ जुलाई तक शांति सेना वापस न लौटाने पर उसे बैरकों में बंद करने तथा दक्षेस सम्मेलन में शामिल न होने की भारत को धमकी।

२४ जून : अंगोला में युद्धविराम। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जाओझियांग 'लोकतंत्र समर्थक आंदोलन' के पक्षधर होने के आरोप में पद से बर्खास्त, चियांग चेमिन पार्टी के नये महासचिव नियुक्त।

२५ जून : ब्रिटेन में जातीय दंगे भड़के, पुलिस द्वारा ८० लोग गिरफ्तार। यूनान के प्रधानमंत्री आंद्रेयास पापेंद्रु की दिल और गुर्दों में गड़बड़ी के कारण स्थिति चिंताजनक।

२६ जून : फिलीपीस में कम्युनिस्ट विद्रोहियों द्वारा एक चर्च पर हमला करके पूजा कर रहे ३९ पुजारियों की हत्या। सात सदस्यीय दक्षेस संगठन की बैठक श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल की अनुपस्थिति के कारण स्थगित।

२७ जून : सोवियत सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री निकोलाई रिजकोव के नये मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए प्रस्तावित छह नामों की नामंजूरी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बाब हाक द्वारा अमरीका के भारत, ब्राजील और जापान विरोधी कदम की आलोचना।

२८ जून : चीनी सरकार द्वारा अपने राजदूतों को विशेष बैठक के लिए पेइचिंग आने का आदेश।

२९ जून : सात में से छह दक्षेस देशों के विदेश सचिवों द्वारा मौजूदा संकट को टालने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कोलंबो भेजने का फैसला।

३० जून : सूडान में सेना द्वारा प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का तख्तापलट।

Bonny Mix
Yummy Goodness of Fruits, Nuts, Wheat, Rice and Corn in a delicious muesli
Wholesome nourishment from Nature's bounty
1
2
3
4
Bonny Mix

बॉनी मिक्स®

नया तत्काल तैयार पॉरिज.
जो है अनाज, फल और मेवों की पौष्टिकता से भरा.

बॉनी मिक्स.
गेहूँ, मक्का, चावल,
नारियल, सेब, खजूर,
किशमिश और काजू का
पौष्टिक मिश्रण.

सभी के लिए स्वाद-भरा पोषण

बॉनी मिक्स संपूर्ण परिवार के लिए पोषक पॉरिज है.... सुबह नाश्ते के लिए या शाम को स्कूल व ऑफ़िस से लौटकर आए सदस्यों को खिलाने के लिए आदर्श. पचाने में हल्का व आसान है इसलिए वृद्ध और बीमारी के बाद स्वास्थ्यलाभ करने वाले व्यक्तियों के लिए भी उत्तम है.

मिनटों में तैयार

बॉनी मिक्स झटपट और आसानी से बनता है. व्यस्त गृहिणियों के लिए वरदान आपको सिर्फ़ इतना करना होगा -

1 एक कटोरे में आवश्यक मात्रा में बॉनी मिक्स डालिए.

2 उसमें धीरे-धीरे पहले से उबाला हुआ दूध मिलाइए.

3 इसे धीरे से फेंटिए. लीजिए पॉरिज तैयार है.

4 हर चम्मच खाने के बाद आपका परिवार इसके स्वाद की तारीफ़ करेगा.

जी हाँ, अपने परिवार को स्वाद और स्वास्थ्य की दुनिया में ले जाइए.... उन्हें बॉनी मिक्स दीजिए.

बॉनी मिक्स®
भारत में पहली बार!

प्रस्तुतकर्ता- ग्लिन्डिया लि. (पूर्वकालीन ग्लैक्सो)
परिवार के लिए पौष्टिक आहार में सबसे भरोसेमंद नाम

बड़ा कौन ?

वीर बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद केन्द्रीय संचार मंत्रालय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अधीन चला गया है। लेकिन उसका सारा काम राज्यमंत्री गिरधर गोमांगो ही देखते हैं। वैसे, जब से संचार मंत्रालय में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में दूर संचार आयोग गठित हो गया है, तब से इस मंत्रालय का दर्जा काफी गिर गया है। वीर बहादुर सिंह ने इस आयोग के गठन का तीव्र विरोध किया था। प्रधानमंत्री के सामने जब यह मामला पेश किया गया, तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह को आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उनको संचार मंत्रालय से हटाकर कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया जायेगा। लेकिन इसके पहले ही पेरिस में उनका निधन हो गया।

दूर संचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सैम पित्रोदा को राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन वे आयोग के अध्यक्ष के अलावा संचार मंत्रालय के सचिव भी हैं। वैसे वे संचार मंत्रालय में ज्यादा बैठते नहीं हैं। लेकिन जब बैठते हैं, तो उनको राज्यमंत्री गिरधर गोमांगो से काफी परेशानी होती है। गिरधर गोमांगो वैसे बहुत सीधे आदमी हैं। लेकिन जब वे राज्यमंत्री की हैसियत से अपने मंत्रालय के सचिव को अपने कमरे में बुलाते हैं, तो सैम पित्रोदा अकसर नहीं आते हैं। सैम पित्रोदा और गिरधर गोमांगो के निजी स्टाफ में इस बात को लेकर अकसर झगड़ा हो जाता है। सैम पित्रोदा का स्टाफ कहता है कि हमारे साहब भी राज्यमंत्री की हैसियत रखते हैं। इसलिए एक दूसरे राज्यमंत्री के यहां वे क्यों जायें? राज्यमंत्री गोमांगो स्वयं हमारे यहां आकर सैम साहब से मुलाकात करें। लेकिन गोमांगो के स्टाफ का कहना है कि सैम पित्रोदा संचार मंत्रालय में सचिव हैं। इसलिए उनको हमारे मंत्री के यहां आना पड़ेगा।

पता चला है कि इधर सैम पित्रोदा और गिरधर गोमांगो ने आपसी बातचीत से यह तय कर लिया है कि दोनों बारी-बारी से एक दूसरे के यहां जाया करेंगे। लेकिन देखने में यही आता है कि सैम पित्रोदा अकसर गिरधर गोमांगो के कमरे में जाने से कतरा जाते हैं। लेकिन गिरधर गोमांगो को इस बात का कोई गिला नहीं है कि सैम पित्रोदा उनकी उपेक्षा करते हैं।

प्रियंका की परीक्षा

आतंकवाद के कारण प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोनों बच्चों—प्रियंका और राहुल—की पढ़ाई घर पर ही होती है। उनको पहले दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की आपत्ति पर दोनों बच्चों के स्कूल से नाम कटाकर उनको घर पर ही मास्टरों के जरिये पढ़ाया जाता है।

इस बार प्रियंका ने १२वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आये हैं। पता चला है कि प्रियंका यह कहती है कि उसने पेपर तो काफी अच्छे किये थे, लेकिन नंबर अच्छे क्यों नहीं आये? जब प्रियंका ने यह बात अपने पिता राजीव गांधी से कही, तो वे टाल गये। लेकिन उसने जब यही बात अपनी मां सोनिया से कही, तो उनको पक्का यकीन हो गया कि प्रियंका की परीक्षा कापियां जांचने में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी है। सोनिया ने राजीव गांधी से अनुरोध किया कि प्रियंका की परीक्षा कापियों की फिर से जांच करने का अनुरोध किया जाये। अंत में राजीव गांधी मान गये। उन्होंने बोर्ड को पिता होने के नाते एक प्रार्थना पत्र भेजा है कि मेरी बेटी प्रियंका को शक है कि उसकी परीक्षा पुस्तिकाओं की जांच में सावधानी नहीं बरती गयी है, इसलिए उनकी फिर से जांच की जाये।

पता चला है कि बोर्ड ने प्रियंका की सारी उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांच कराने के लिए परीक्षकों के सुपुर्द कर दिया है। अब देखना है कि प्रियंका के नंबर बढ़ पायेंगे या नहीं।

इलाहाबाद सीट का दावा

हेमवती नंदन बहुगुणा के निधन के बाद जब लोकदल-ब कांग्रेस में विलीन हुआ था, तो यह समाचार अखंडित रहा था कि राजीव गांधी ने यह आश्वासन दिया है कि श्रीमती कमला बहुगुणा इलाहाबाद लोकसभाई सीट से लड़ेंगी, शेखर बहुगुणा को बारा (इलाहाबाद) विधानसभा से टिकट मिलेगा और विजय बहुगुणा को गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ाया जायेगा। लेकिन जब राजीव गांधी बड़गढ़ (बांदा) में २५० करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 'फ्लोट ग्लास' कारखाने की बुनियाद रखने के बाद कानपुर पहुंचे, तो इस स्थिति में पेंच पड़ गया। समाचारों के अनुसार उन्होंने कहा है कि बहुगुणा-परिवार को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, प्रत्याशियों का चयन योग्यता के अनुसार होगा। यह बात इलाहाबाद से गये उस शिष्टमंडल को कही बतायी जाती है जो उनसे कानपुर में मिला था। इस शिष्टमंडल में इलाहाबाद क्षेत्र के दो विधायकों के अतिरिक्त शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रंजना वाजपेयी भी थीं जो केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी की पुत्रवधू और इलाहाबाद शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी की पत्नी हैं। राजीव गांधी ने इस शिष्टमंडल को उपर्युक्त बात कही या नहीं कही, इसको तो दावे के साथ कहना संभव नहीं, लेकिन इससे एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि श्रीमती बहुगुणा का इलाहाबाद सीट के लिए दावा बिना चुनौती के नहीं रहेगा।

◆

युवा वर्ग के
स्वर्णिम भविष्य का आधार

अगस्त १९८९ के वार्षिकांक से

आई.ए.एस. परीक्षा, 1988-89
महिलाओं में प्रथम

कु. शालिनी छाबड़ा से
विशेष भेंटवार्ता

आकर्षक
सामग्री का भण्डार

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक
स्वाधीनता के स्वर
भारत-भारती

१२वें
सफल वर्ष में
प्रवेश

युवा वर्ग के समग्र विकास
के लिये
पत्रिका एक-उद्देश्य अनेक

व्यक्तित्व विकास
चरित्र निर्माण
राष्ट्र सेवा

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

सही मार्गदर्शन-प्रेरक ज्ञानवर्धन

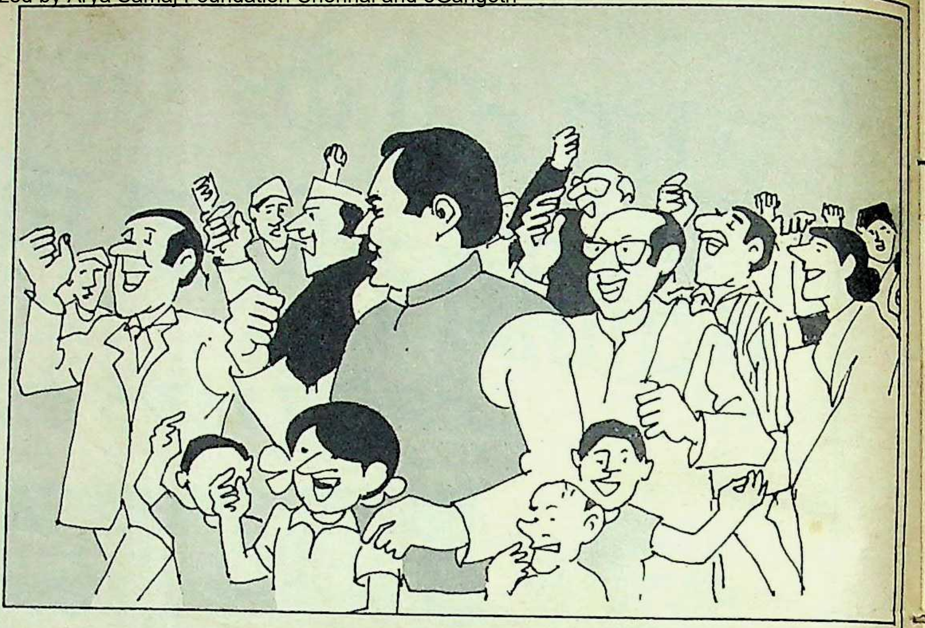

चलो नारे लगाओ !

७ रेसकोर्स में 'दर्शन' का दिन था। अंत्री (अफसर), मंत्री और संत्री (कार्यकर्ता) सफेद लबादों में कफनियाये दमघोंटू उमस में इधर-उधर बिखरे ईरान-तूरान की बहस में पसीने-पसीने हो रहे थे। दूसरी ओर, जगह-जगह लान की विदेशी घास पर देसी घास (जनता) सुरक्षा की काली बिल्लियों से घिरी सहमी-सहमी बाड़ों में बिछी (बैठी) हुई थी। उस पर नीचे से विदेशी घास गरम भाप उगल रही थी, तो ऊपर से सूर्य देवता कहर बरपा किये हुए थे। मनाही नहीं थी, लेकिन पंच-सितारा माहौल में जनता अपने-अपने अंगोछों से चेहरों का पसीना पोंछना और उसे घुमाकर हवा कर लेने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। जब उन बाड़ों में करीब उनके नेता (सांसद या भावी सांसद) पहुंचते, तो जनता के चेहरों पर आशा की किरण छा जाती। घुरहू पूछते, "नेताजी, हमार परेसानी दूर तो हो जायी?" नेताजी उसे आश्वासन देते, "हां भाई, हां। यह देखो तुम्हारा प्रार्थनापत्र सबसे ऊपर ही लगा है। अब पंचायत का सरपंच खुद आकर तुम्हारी भैंस तुम्हारे छप्पर के नीचे बांधेगा।" इसी बीच फकीरे बोल उठते, "हुजूर, हमार लड़कवा के जवाहर रोजगार जोजना मां नौकरी...।" नेताजी उसे हाथ हिलाकर संतोष दिलाते, "मिलेगी, मिलेगी। तुम्हारे लड़के को नौकरी जरूर मिलेगी। यह देखो, तुम्हारी एप्लीकेशन हमारे हाथ में है। बस हाथ को याद रखो तुम, सबका कल्याण होगा।" वाक्य समाप्त नहीं हो पाया था कि घूंघट के अंदर से रामपति बोल उठी, "सरकार, हमरा मनई (पति) के दारोगाजी से बचा ले...।" नेताजी, "चिंता मत कर। तू तो ३० प्रतिशत में है। दारोगाजी का तबादला करा दिया जायेगा।" रामपति अपनी धोती के पल्लू से अपने आंसू पोंछे कि उसके पहले रामू, कल्लू, लल्लू, रामप्यारी आदि-अनादि उठकर अपनी-अपनी समस्याओं की तरफ नेताजी का ध्यान खींचने लगे। नेताजी भड़क उठे, "बैठ जा सालो, एक तो पूरा खर्चा करके दरबार में लाये। यहां तुम लोगों ने नौटंकी शुरू कर दी। खबरदार जो किसी ने जुबान खोली।" जनता सहम कर बैठ गयी, तो नेताजी नरम पड़ गये और अपने हाथ का पंजा दिखाते हुए बडी मिठास से बोले, "अरे भाई, हम तुम्हारी समस्याओं पर ही दरबार से बात करने आये हैं। तुम लोग इतना परेशान काहे हो रहे हो। हम तुम लोगों की सारी समस्याएं सुलझा देंगे। शांति से बैठो।" जनता अपने बाड़े में इस आशा के साथ बैठ गयी कि उसकी आज सारी समस्याएं सुलझ जायेंगी।

रेसकोर्स के पूरे लान में मुल्क की समस्याएं मुंह बाये बैठी हुई थीं। नौकरी की समस्या, पुलिस अत्याचार की समस्या, आतंकवाद की समस्या, सवर्णों द्वारा हरिजनों को परेशान किये जाने की समस्या, महिलाओं के शोषण की समस्या, बंधुआ मजदूरों की समस्या, पानी-बिजली की समस्या, मकानों की समस्या, कपड़े की समस्या, नौकरी मिल जाने के बाद वेतन-बढ़ोत्तरी की समस्या, सांप्रदायिक समस्या, हिंसा की समस्या...समस्या... समस्या और समस्या। और इन सबके ऊपर लोकसभा का टिकट प्राप्त कर लेने की सबसे 'ज्वलंत समस्या'। लान में बैठी जनता अपने मन में अपनी समस्या के हल हो जाने के लड्डू फोड़ रही थी। दूसरी ओर, सफेद खादी में लिपटे नेता लोकसभा का टिकट पा जाने की लालसा में डूब और उतरा रहे थे।

अंदर रेसकोर्स के वातानुकूलित कक्ष में दरबारियों के कागजी घोड़े दौड़ रहे थे। अभी दरबार अंदर-के-अंदर यानी अपने निजी कक्ष में बैठे काफी की प्याली में मुल्क की सारी समस्याओं का तूफान देख रहे थे। धवन उनको वहीं छोड़कर 'दर्शन' की तैयारियां देखने के लिए अपने कक्ष में आ गये थे। जार्ज अदर ही काफी की प्याली के तूफान पर नजर जमाये खड़े थे। कैप्टन सतीश शर्मा बगल में बैठे अपनी काफी की प्याली दरबार को दिखाते हुए कह रहे थे, "अमेठी में मैंने सारे तूफानों को जमीन पर उतार दिया है। आप जाओ या न जाओ, वहां का चुनाव पूरी तरह सुरक्षित है।" दरबार खुश थे।

वातानुकूलित कक्ष में दरबारी जमे हुए छक्के-अट्ठे मार रहे थे। उसी समय दरबार के कुछ गुमाश्ते (प्रेक्षक) पहुंच गये। दरबार की तरफ से इन लोगों को विभिन्न राज्यों में यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि कौन-सी जगह किसको टिकट दिया जाये, ताकि वह चुनाव जीत सके। गुमाश्तों को देखकर केसरीजी (सीताराम) उनके करीब हो लिये, "क्या पता लगाकर आये प्रेक्षक महोदय? हम लोगों के लिए कैसी चुनावी फिजा है?" प्रेक्षक गोपनीयता के डर से केसरीजी से कटने लगे, "कुछ नहीं, बस यों ही देखा। कुछ खास तो नहीं देख पाये। वैसे सब ठीक ही है।" केसरीजी ने प्रेक्षक को दबोच लिया, "नये-नये मुसलमान हुए हो, तो प्याज खा रहे हो। दाई से पेट बचाकर कहां जाओगे? जितनी तुम्हारी उम्र है, उससे दुगने सालों से हम यह काम कर रहे हैं। हमारे शरीर में खून नहीं राजनीति ही बह रही है।" प्रेक्षक सकपका कर केसरीजी के चंगुल में आ गया, "अरे खजांचीजी, अब आपसे क्या कुछ छुपा हुआ है? एक-एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में

दस-दस उम्मीदवार हैं। एक को टिकट मिलेगा, तो नौ-नौ उसको हराने में लग जायेंगे। हम वीपी सिंह के हराये से रहे। हरायेंगे तो हमारे ही दलवाले हमको।'' केसरीजी ने प्रेक्षक को इशारा किया, ''अरे धीमे बोल मट्टी के माधव। तेरे से पहले इसी क्षेत्र में पहले भी एक प्रेक्षक भेजा जा चुका है। उसने जब तेरी जैसी रिपोर्ट दी, तो उसकी छुट्टी कर दी गयी। अब तू भी वैसी ही रिपोर्ट देगा, तो तेरी भी छुट्टी हो जायेगी। मेरी मान तो आईबी मार्का रिपोर्ट दे दे, जिसका कोई अर्थ ही न निकलता हो। तेरा राज्यसभा का 'टर्म' भी पूरा होनेवाला है। गोलमोल रिपोर्ट देगा, तो पुरस्कारस्वरूप तुझको फिर से नामीनेशन मिल जायेगा।'' प्रेक्षक ने केसरीजी के प्रवचन के आगे अपनी आंख फाड़ दी, ''सत्य वचन आचार्य केसरीजी, राजनीति भी क्या चीज है! जो दिखता है, वह सत्य नहीं और जो नहीं दिखता है, उसी में राजनीति सारी संभावनाएं दिखाती है।'' केसरीजी ने प्रेक्षक की गंजी चांद पर चपत जमा दी, ''बच्चा, इतने इमोशनल हुए, तो गच्चा खा जाओगे। आज की तारीख में जिसका सिक्का चलता हो, उसकी जय-जयकार करो। खुद खाओ और उड़ाओ तथा बाल बच्चों के लिए भर ले जाओ।'' प्रेक्षक द्रवित होकर केसरीजी के चरणों में यह कह कर झुका, ''हूं जाति का ब्राह्मण, लेकिन...।'' पीछे से दरबार के आ जाने से प्रेक्षक का धर्म भ्रष्ट होते-होते रुक गया।

दिल्ली दरबार को कक्ष में पहुंचते ही बताया गया, ''सर, आज देश के छह राज्यों की ग्रामीण जनता आपके 'दर्शन' करने के लिए आयी है। पंचायती राज और जवाहर रोजगार योजना से मुल्क का पूरा-का-पूरा ग्रामीण परिवेश तेजी से बदलने लगा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह पैदा हो रहा है। जो प्रतिनिधि इन लोगों को आपके दरबार में लाया है, उसका पूरा बायोडाटा लोकसभा के उम्मीदवार के लिए कंप्यूटर में डाल दिया गया।'' दरबार ने इस पर मात्र 'हूं' किया, तो उनको आगे बताया गया, ''सर, छह महीने पहले जो आपका 'दर्शन' कार्यक्रम मात्र एक घंटे का शुरू किया गया था, वह पब्लिक की डिमांड पर दो घंटे का कर दिया गया। लेकिन इधर पब्लिक की तरफ से हम लोगों पर जबरदस्त प्रेशर है कि दर्शन का समय और बढ़ाया जाये। अगर आप अनुमति दें, तो उसे तीन घंटे का कर दिया जाये।'' दरबार ने इस पर छोटा सा 'हां' कह दिया। दरबार को उसके बाद बताया गया, ''सर, आज के 'दर्शन' प्रोग्राम में आपके ३२ ग्रुप फोटोग्राफ हैं। दरबार की शान में लिखी गयी तीन पुस्तकों का विमोचन करना है। चार महिला संगठनों की प्रतिनिधियों को आपको देखना है, यानी मिलना है। दो घंटे सात मिनट और ५१ सेकिंड के कुल 'दर्शन' कार्यक्रम में आपके पांच भाषण होंगे।'' पास खड़े मणिशंकर अय्यर ने मोटे कार्ड पर पांचों भाषणों के 'नोट्स' थमाते हुए कहा, ''आतंकवाद के खिलाफ आप जो दो दर्जन भाषण दे चुके हैं, वही देना है। बस उसको थोड़ा-सा 'अप टू डेट' पिछले दिनों मोगा में हुई हत्याओं से कर लेना है। उसको मैंने शुरू में ही ले लिया है। दूसरा भाषण जवाहर रोजगार योजना पर तो आपका पूरी तरह तैयार ही है। बस उसमें यही जोड़ना है कि हम शहरी इलाकों के लिए भी ऐसी ही रोजगार योजना बना रहे हैं। तीसरा भाषण 'अग्नि' पर है। सर, उसमें वही पुराने 'नोट्स' हैं। चौथा भाषण पंचायती राज पर है। उसमें तो आप दर्जनों बार झंडे गाड़ चुके हैं। पाचवां और आखिरी भाषण विपक्ष पर भरपूर हमले से संबंधित है। मैंने इसके 'नोट्स' तैयार किये थे। लेकिन उसके बाद कल्पनाथ रायजी ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके उसे पूरी तरह अपनी शैली में कर दिया है।'' पहले के चार भाषणों के कार्डों को तो दरबार ने कुरते की जेब में रख लिया। पांचवें भाषण के कार्ड्स पर लिखे गये नोट्स पर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया, ''इसमें तो काफी गालीगलौज है। मुझे क्या...।'' पास खड़े कल्पनाथ राय ने मणिशंकर को पीछे धकिया दिया, ''सर, हम विपक्ष को गाली नहीं देंगे, तो क्या उनकी पूजा करेंगे? मुल्क अब आपके मुंह से कल्पनाथी शैली में भाषण सुनने को उतावला हो रहा है।'' दरबार धीरे से बुदबुदाये, ''इसमें जो आरोप विपक्ष पर लगाये जा रहे हैं, वे तो मुझे झूठे लग रहे हैं।'' कल्पनाथ राय ने अपनी जांघ खुजलाते हुए कहा, ''सर, प्रेम और युद्ध में सच और झूठ कुछ नहीं होता है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर कोई झूठ सौ बार बोला जाये, तो वह सच बन जाता है। आप विपक्ष के बारे में यह सब बोलते जायें, सब कुछ सच में बदल जायेगा।'' इसी समय धवन ने दरबार को इशारा किया कि 'दर्शन' का समय हो गया है। आपको अब लान में चलना है। सुरक्षा पूरी तरह 'अलर्ट' हो गयी है।

दिल्ली दरबार 'दर्शन' देते हुए जब घुरहू के बाड़े के पास पहुंचे, तो उसके प्रतिनिधि ने दरबार को उन लोगों का परिचय दिया, ''सर, ये लोग मुल्क के बहुत पिछड़े इलाके से आपके दर्शन करने के लिए आये हैं। इन लोगों ने आपको पंचायती राज और जवाहर योजना के लिए यह लिखित बधाई दी है। ये लोग रोजगार पा कर बहुत खुश हैं।'' फिर धीरे से उस प्रतिनिधि ने एक और प्रार्थनापत्र देते हुए कहा, ''सर, ये लोग यह भी कहने आये हैं कि इस क्षेत्र से मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाये।'' इसके बाद उस प्रतिनिधि ने एक और कागज दरबार को थमाते हुए कहा, ''सर, उस क्षेत्र की कुछ और समस्याएं भी हैं। जैसे वहां कोई डिग्री कालेज नहीं है। न ही कोई इंजीनियरिंग कालेज है। अगर वहां कालेज खुल जाये, तो इन पिछड़े लोगों के बच्चों को पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधा हो जायेगी।'' दरबार ने प्रतिनिधि से कागज लेकर पास खड़े एक अधिकारी को दे दिया और हाथ दिखाते हुए घुरहू, फकीरे, रामपति, रामू, कल्लू, रामप्यारी आदि इत्यादि के अभिवादन को स्वीकार करते हुए कहा, ''आप लोगों की समस्या को मैं मजबूती से जान गया हूं। आप लोग निश्चिंत होकर जायें और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करें। मैं देखूंगा कि आपकी (डिग्री कालेज खोलने की) समस्या कैसे हल होगी।'' दिल्ली दरबार सुरक्षा के घेरे में जब घूम कर दूसरे बाड़े की तरफ बढ़े, तो घुरहू, फकीरे, रामपति आदि टुकर-टुकर निहारते रहे। इस पर बाड़े के प्रतिनिधि ने आपा खो दिया। वह उनकी तरफ मुखातिब होकर चिल्लाये, ''सालो, इतना खर्चा करके तुम लोगों को यहां लाये और तुम लोग टुकर-टुकर ताक रहे हो? नारे लगाओ—दिल्ली दरबार की जय।'' बाड़े की भीड़ दिल्ली दरबार की जय-जयकार के नारे लगाने लगी। उसके बाद प्रतिनिधि ने कहा, ''अब मेरी जयकार के नारे लगाओ।'' बाड़े की भीड़ ने प्रतिनिधि की जय-जयकार के नारे लगाये। जब नारे रुक गये, तो घुरहू ने अपने प्रतिनिधि से पूछा, ''हुजूर, गांव का सरपंच हमार भैंस खोल ले गवा है। का अब भैंस मिल जाई?'' प्रतिनिधि उसे कुछ पट्टी पढ़ाये कि उसके पहले ही रामपति रोने लगी, ''सरकार, हमार मनई के दारोगा जी...।'' प्रतिनिधि भड़क उठे, ''चुप रहो। तुम लोग गधे हो।'' फिर उन्होंने अपने स्वर को संयत कर लिया, ''देखो भाइयो, यह सब हमने तुम्हारी ही समस्या सुलझाने के लिए किया है। इस समय तुम लोगों से बड़ी समस्या मेरी है। अगर मुझे टिकट मिल गया और तुम लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया, तो तुम लोगों की समस्याएं मैं मिनटों में सुलझा दूंगा। समझ गये न? चलो नारे लगाओ...।'' बाड़े की भीड़ नारे लगाने लगी।

> **वह उनकी ओर मुखातिब होकर चिल्लाये, ''सालो, इतना खर्चा करके तुम लोगों को यहां लाये और तुम लोग टुकुर-टुकुर ताक रहे हो? नारे लगाओ—दिल्ली दरबार की जय!'' बाड़े की भीड़ दिल्ली दरबार की जय-जयकार के नारे लगाने लगी।**

—दरबारी लाल

माँ का प्यारा,
राजदुलारा
करे शरारत
सुबह-व-शाम
खुश हो, या हो रूठा
फर्श पर लोटे
बारम्बार
लेकिन रहें माँ बेफिक्र
रातदिन
क्योंकि घर है
कीटाणुहीन
करे गृहिणी सावधानी
निर्विकल्प इसीलिए
गाढ़ा काला फिनियल
अल्प कर रोज व्यवहार
बारम्बार
भरोसा इस पर
अपार —

PHENEOL
LAMP
BLACK DISINFECTANT FLUID
BENGAL CHEMICALS & PHARM
गाढ़ा
काला
कई एक बूंद...
हो गई
घरद्वार की सफाई

बेंगॉल केमिकल का
लैम्प ब्रैन्ड
फिनियल
आदि, विशुद्ध, बेमिसाल

BC
PL

बेंगॉल केमिकल्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स लि:
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

ABP/BCP/1/88/HIN

एनटीआर का 'महर्षि विश्वामित्र'

अपने को पूर्णतया राममय माननेवाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामाराव को रामकथा के एक विशिष्ट चरित्र 'महर्षि विश्वामित्र' पर फिल्म बनाने के सपने को साकार करने में पूरे १२ वर्ष लग गये। इस फिल्म का मुहूर्त वे इस वर्ष रामनवमी को करना चाहते थे, लेकिन परिवार में हुए एक हादसे के कारण मुहूर्त टलता रहा। अंत में निर्गुण-राम के आख्याता कबीर के जन्म दिन १८ जून '८९ को वे इस फिल्म का मुहूर्त कर पाये।

फिल्म-अभिनय के ८ वर्ष के लंबे संन्यास के बाद 'महर्षि विश्वामित्र' के कास्ट्यूम तथा मेकअप में कैमरे के सामने आ खड़े हुए एनटी रामाराव की जिंदगी में १२ के आंकड़े का किस हद तक महत्व रहा, पता नहीं, लेकिन मुहूर्त शाट देखने के लिए विशेष रूप से एकत्रित उनके लगभग १२ हजार प्रशंसकों के अलावा दक्षिण सिनेमा के जाने-माने १२ सितारे (कमल हासन, उर्वशी, शारदा, रावगोपाल राव आदि) तथा भारतीय राजनीति के विपक्ष के लगभग १२ कर्णधार (विश्वनाथ प्रताप सिंह, एम करुणानिधि, चौधरी देवीलाल, प्रफुल्ल महंत, पीके

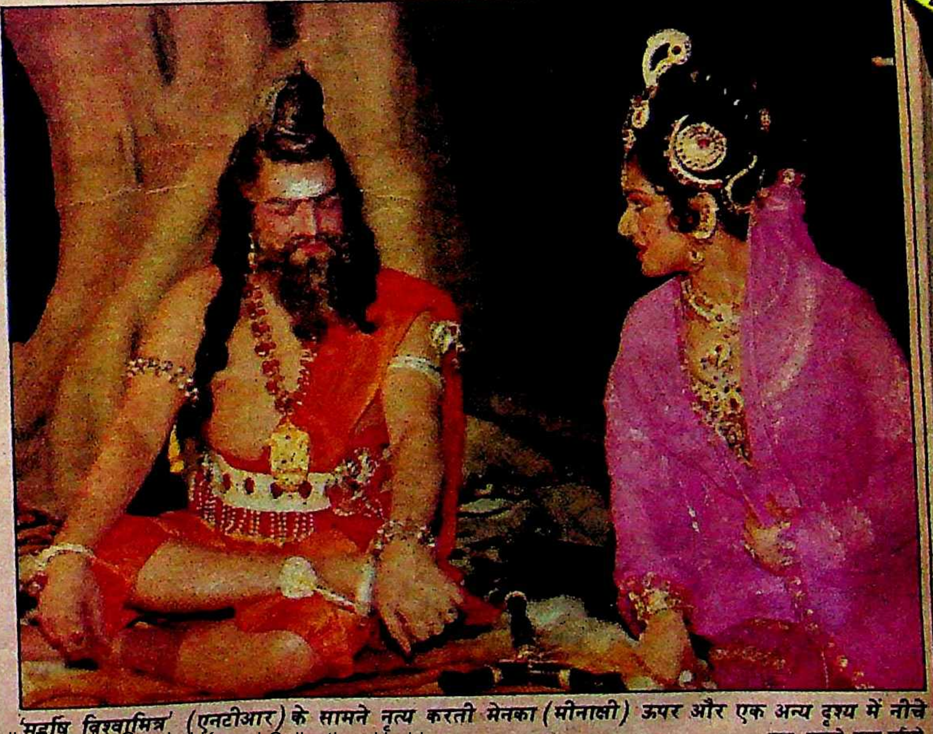

'महर्षि विश्वामित्र' (एनटीआर) के सामने नृत्य करती मेनका (मीनाक्षी) ऊपर और एक अन्य दृश्य में नीचे

छाया : बाब जो. बनता स्टूडियो

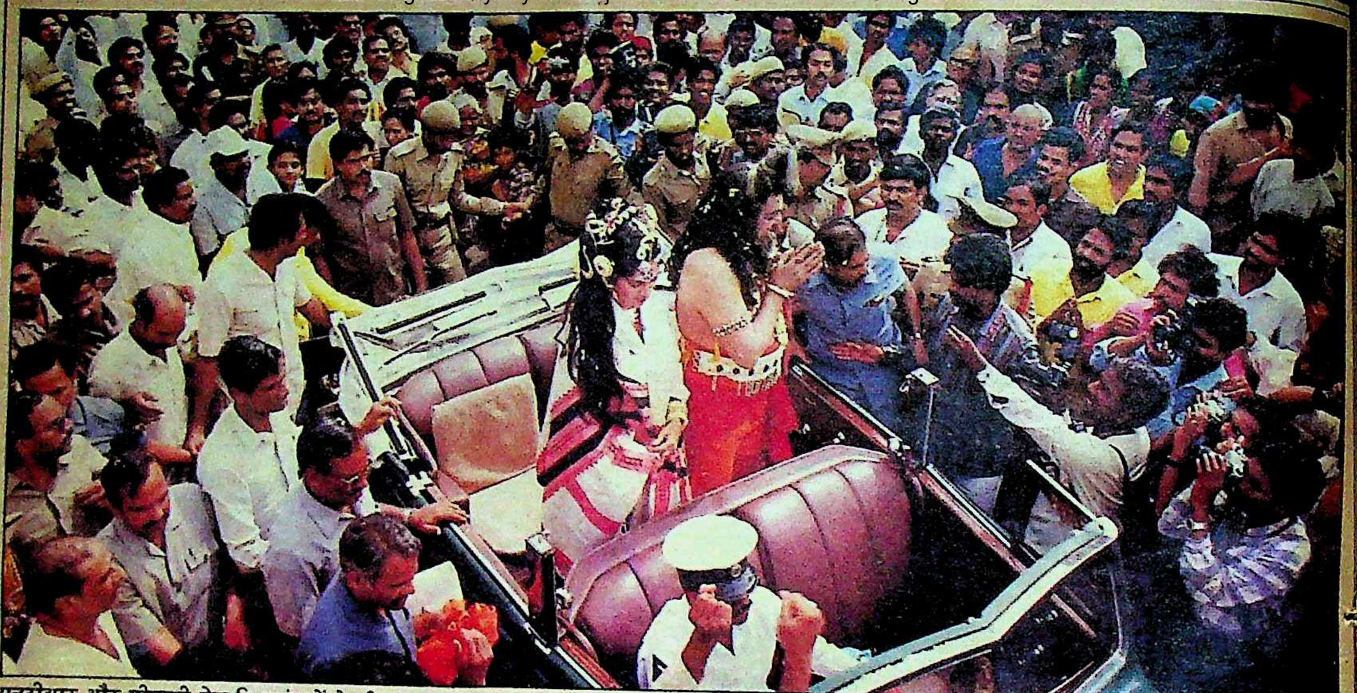

एनटीआर और मीनाक्षी शेषाद्रि प्रशंसकों के बीच

उन्नीकृष्णन, दिनेश गोस्वामी, एम मारन आदि) जरूर उपस्थित थे और टीवी सेट पर मुहूर्त के 'लाइव शाट' का आनंद ले रहे थे।

हमेशा अपनी उम्र से आधी तथा तिहाई कम उम्रवाली अभिनेत्रियों के साथ नायक की भूमिका निभानेवाले एनटीआर जब अपनी पौत्री की उम्रवाली, दक्षिण भारत में ही जन्मी, अल्पवसना अप्सरा मेनका के मेकअप में फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि को अपने राजनीतिक दोस्तों से मिलाने के लिए उनके कक्ष में ले गये, तो भूख और गरीबी से त्रस्त फटेहाल महिलाओं के बीच भाषण देनेवाले सारे नेता जरूर रोमांचित हो उठे होंगे।

'महर्षि विश्वामित्र' का निर्माण एनटीआर के दीर्घकालीन स्वप्न की पूर्णाहुति है या राजनीतिक शतरंज का नया मोहरा या तेलुगू में निरंतर बढ़ते अंदरूनी विरोध और विद्रोह के विरुद्ध फिल्मों में पुनः वापस लौटने की एनटीआर की धमकी अथवा आगामी आमचुनाव में देशव्यापी चुनाव-प्रचार का एक नया (दक्षिण फिल्म निर्माण की शैली में) हथकंडा? एनटीआर इन सवालों के जवाब में इस तरह मुस्कराते हैं जैसे यही उनका जवाब भी है, "मैं राजनीति और कला को अलग नहीं मानता, दोनों का मकसद जनता की सेवा करना है। महर्षि विश्वामित्र पर फिल्म बनाने तथा उनकी भूमिका निभाने का मेरा सपना इसलिए था कि वे हरिजनों और निर्बलों के रक्षक-संत थे। उन्होंने महाराजा हरिश्चंद्र की सत्य-परीक्षा लेकर सत्य के महत्व को समझा था। इसे बनाने से रोकने के लिए लोगों (उनके विरोधियों) ने बहुत कोशिशें कीं, लेकिन अब इसे कोई नहीं रोक सकता। यह 'महर्षि विश्वामित्र' की रचना है। वे हमारी राजनीति के आदर्श पुरुष हैं।"

विश्वामित्र की वेशभूषा में जनता को संबोधित करते हुए एनटीआर

छह वर्ष पहले जब एनटीआर ने 'महर्षि विश्वामित्र' के निर्माण की घोषणा की थी, तभी उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया था कि इस फिल्म से होनेवाली सारी आय उनकी दिवंगत पत्नी की याद में बन रहे अस्पताल के निर्माण में खर्च की जायेगी। यह अस्पताल वे महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनवा रहे हैं। एनटीआर की पत्नी का निधन अक्तूबर १९८४ में हुआ था।

मेनका की तलाश : फिल्म की तैयारी पूरी हो जाने के बाद मुख्य समस्या पात्रों के चुनाव की थी। विश्वामित्र की केंद्रीय भूमिका एनटीआर खुद निभा रहे थे। राम, हरिश्चंद्र तथा दुष्यंत की भूमिका अपने पुत्र बालकृष्ण को सौंप रखी थी, बाद में राम की भूमिका उन्होंने प्रख्यात वायलिनवादक उमरेशन को तथा लक्ष्मण की भूमिका उनके छोटे भाई गणेशन को सौंप दी। सवाल मेनका, सीता, शैव्या और शकुंतला की भूमिकाओं पर टिक गया। उनमें मेनका को छोड़कर शेष महिला भूमिकाएं कम महत्वपूर्ण थीं।

एनटीआर के दिमाग में मेनका की भूमिका के लिए श्रीदेवी उस समय जंचीं, जब हैदराबाद में हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में दीपबालिका की जिम्मेदारी निभाने के लिए

अपनी सारी शूटिंग छोड़कर वहां पहुंची थीं। फिर श्रीदेवी मूलतः तेलुगू भाषी हैं—ग्लैमरस, नृत्यप्रवीण तथा खूबसूरत भी। मेनका के रूप में उनसे सही कलाकार दूसरा नहीं था। लेकिन तमिलनाडु में हुए पिछले चुनाव में जब उन्होंने अपने कांग्रेसी-उम्मीदवार पिता के पक्ष में खुलकर चुनाव-प्रचार किया, तो क्रुद्ध एनटीआर ने अपनी सूची से उनका नाम काट दिया। इसके बाद उन्होंने रेखा, जयाप्रदा , भानुप्रिया, मीनाक्षी शेषाद्रि, माधुरी दीक्षित, मंदाकिनी तथा दक्षिण की कई अभिनेत्रियों की फिल्मों के नृत्य-शाट देखे। रेखा उन्हें पसंद थीं, लेकिन जब उन्हें उनके 'मूडी' होने की बात बतलायी गयी, तो उनका नाम भी खारिज कर दिया। इसी तरह तेलुगूभाषी तथा आंध्र प्रदेश में जन्मी जयाप्रदा एवं भानुप्रिया के बारे में भी विचार किया गया। जयाप्रदा खूबसूरत तथा नृत्यकुशल तो हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सेक्स अपील तथा फिगर में ग्लैमर उस तरह का नहीं है, जैसा कि अप्सरा मेनका के चरित्र में होना चाहिए था। अंत में उनका ध्यान मीनाक्षी तथा भानुप्रिया पर टिका और अंततः मीनाक्षी बाजी मार ले गयीं।

'महर्षि विश्वामित्र' कैसी बनेगी, यह तो बाद की बात है, लेकिन विपक्षी दल तथा तेलुगूदेशम में एनटीआर का दबे स्वर में विरोध हो रहा है। इंका विधायक डा० वाईएस राजशेखर रेड्डी ने एनटीआर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म के मुहूर्त पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। विभिन्न मंत्रालयों (भवन, सड़क तथा लोक निर्माण, विद्युत आदि विभाग) के कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के लिए नाचरम में तैनात किया गया था। मीनाक्षी शेषाद्रि की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर एक पुलिस उपायुक्त, दस इंसपेक्टर सहित पुलिसकर्मियों की एक फौज ४० गाड़ियों के साथ तैनात थी। अब यह भी इत्तिफाक है कि बेचारे इन्हीं पुलिसवालों को भीड़ में खो गया मीनाक्षी शेषाद्रि का कीमती हेयरपिन भी तलाश कर देना पड़ा था।

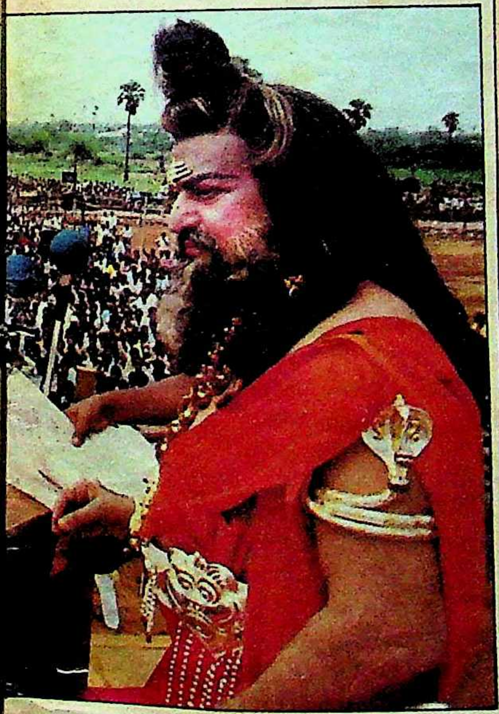

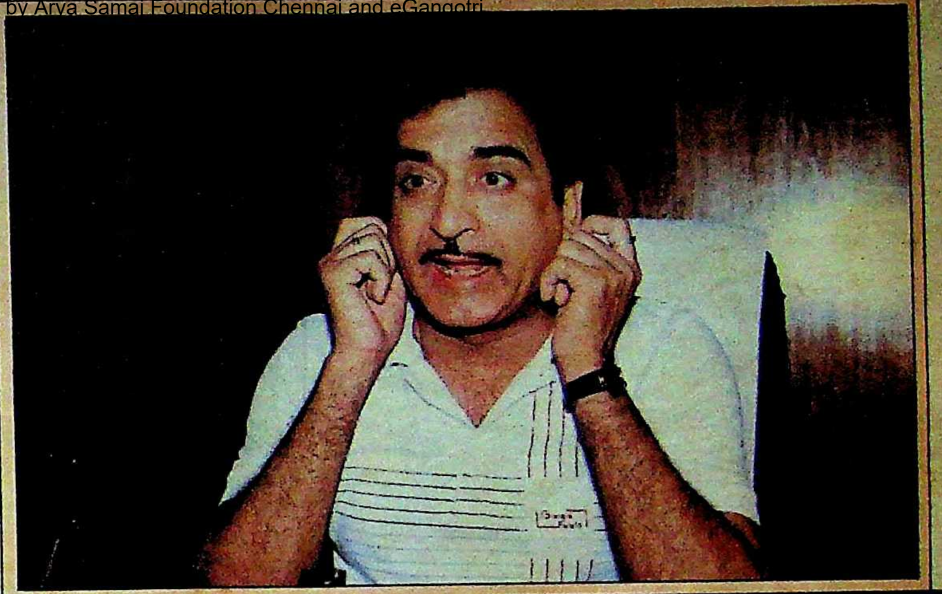

केके तिवारी का ड्रामा

नाटकीय भंगिमाओं के साथ रोचक टिप्पणियां करने में सूचना प्रसारण राज्यमंत्री केके तिवारी का कोई जवाब नहीं। 'माया' से साक्षात्कार (पढ़िए इसी अंक में) के दौरान एनटीआर के बारे में की गयी उनकी रोचक टिप्पणी और तदनुकूल उनकी मुद्राएं यहां प्रस्तुत हैं : "एनटी रामाराव महिलाओं की तरह कानों में बालियां डालकर नाक में कील डाल कर और साड़ी पहन कर इसलिए सोता है कि वह प्रधानमंत्री बन जाये।"

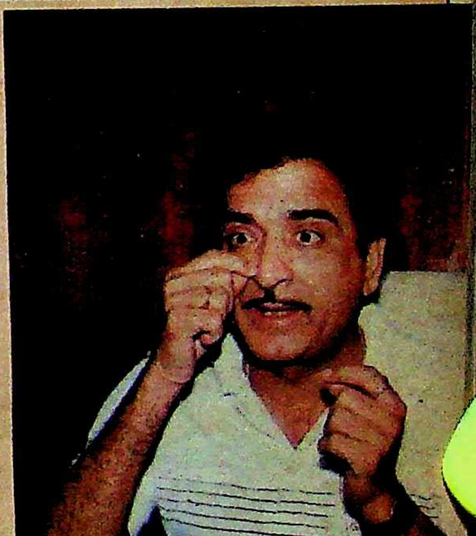

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

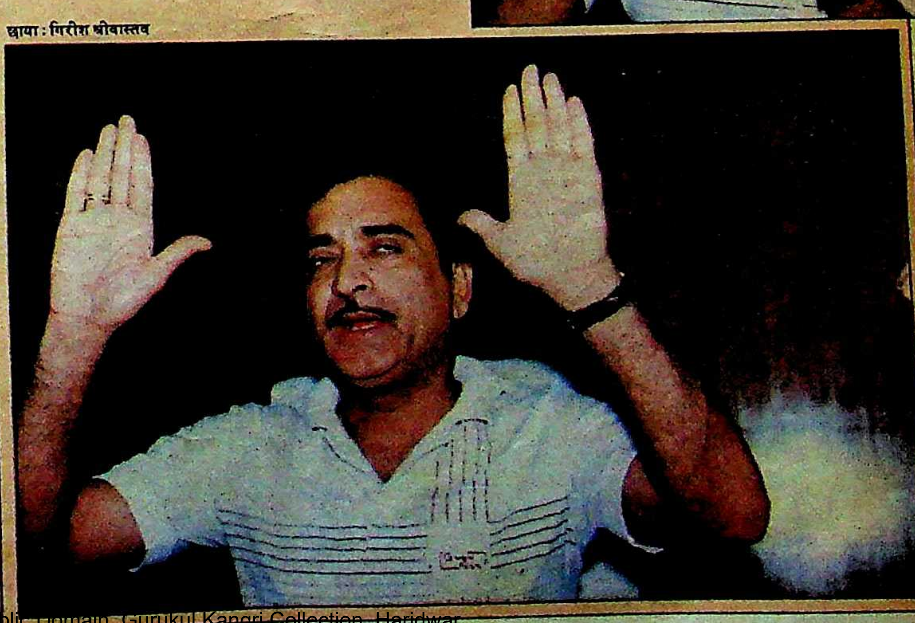

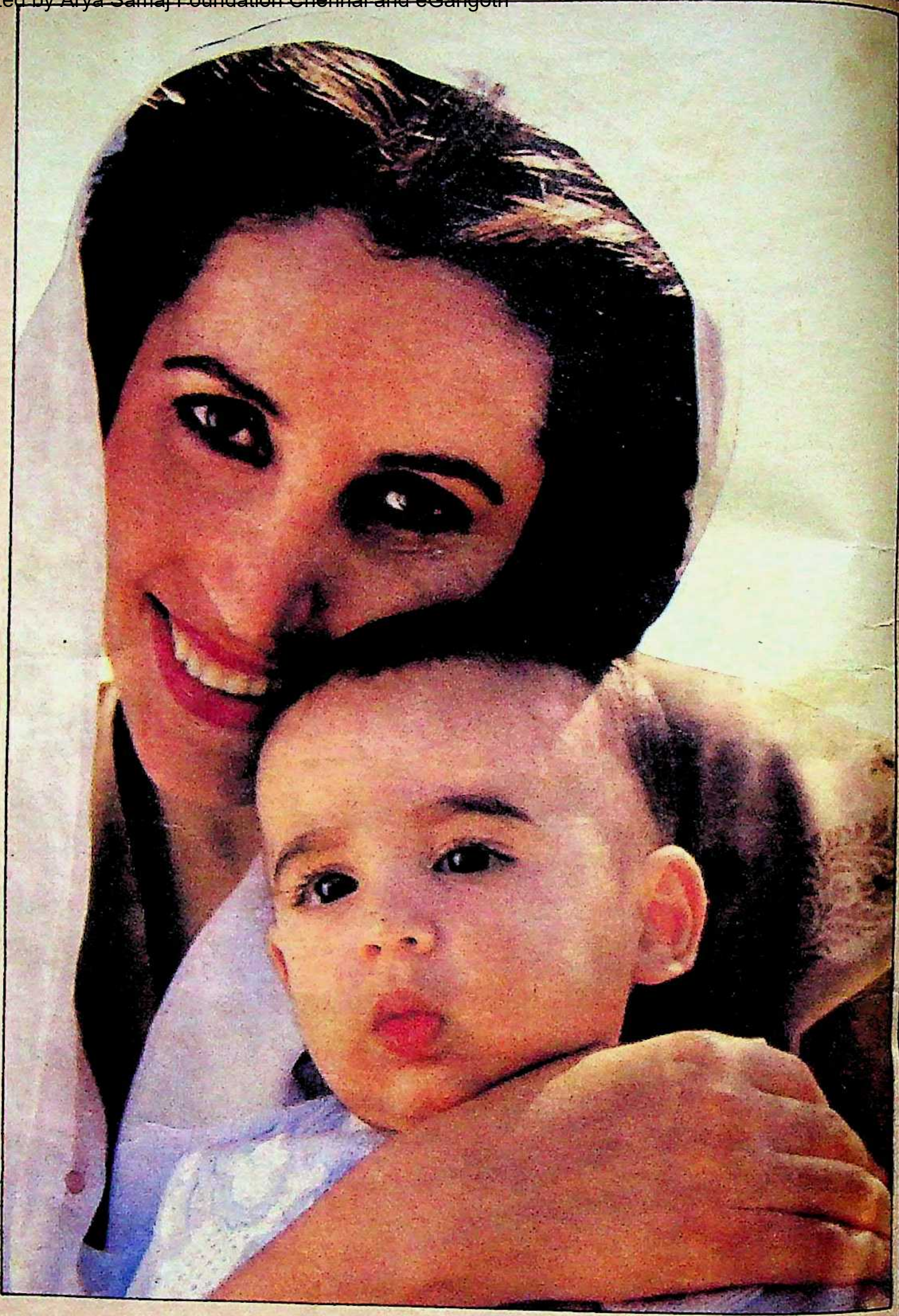

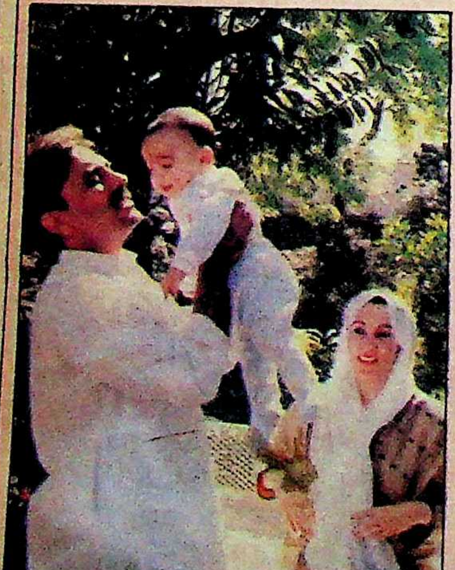

बेनजीर भुट्टो के आत्मीय क्षण

बेनजीर भुट्टो कई मामलों में अव्वल हैं। वे इस्लामिक देशों में पहली प्रधानमंत्री ही नहीं, वे पहली ऐसी प्रधानमंत्री भी हैं जो नवजात शिशु की मां हैं। उनका काफी समय राजनीति के रेगिस्तान में भटकते गुजरता है। इसलिए जब कभी उन्हें निजी क्षणों का नखलिस्तान उपलब्ध होता है, तो वे अपने पुत्र बिलावल और पति जरदारी के साथ उसका भरपूर आनंद उठाती हैं। ऐसे ही आत्मीय क्षणों के दो दृश्य यहां प्रस्तुत हैं :

मोतीलाल वोरा : दब्बू या दबंग ?

गुटीय राजनीति में विश्वास न रखने के लिए मशहूर मोतीलाल वोरा ने जनवरी १९८९ में जब दुबारा मध्यप्रदेश की बागडोर संभाली, तो उन्होंने ऐसी कार्यशैली अपनायी जिससे उनकी सरकार को 'खड़ाऊं सरकार' तथा उन्हें लल्लू कहनेवाले सकते में आ गये। आखिर इस बार वे कैसे शासन चला रहे हैं कि वे दब्बू के बजाय दबंग माने जा रहे हैं ?

समय के साथ-साथ राजनीति भी करवट लेती है...१९८५ में मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने, तो वे सबकी 'साझा पसंद' थे। पंच-महारथियों—सिंधिया, अर्जुन सिंह, कमलनाथ, सेठी और विद्याचरण—समेत सभी विधायकों और सांसदों ने उनकी ताजपोशी का स्वागत किया था। मगर, जनवरी १९८९ में जब वोरा दुबारा मुख्यमंत्री बने, तो परिस्थितियां सर्वथा भिन्न थीं। वे सबकी 'साझा पसंद' के बजाय 'समझौता मुख्यमंत्री' थे। उन्हें राजीखुशी स्वीकार करनेवाले कम थे, विवशता में स्वीकार करनेवाले ज्यादा। जिस व्यक्ति ने गुटीय राजनीति के खेल में न कभी हिस्सा लिया और न ही कभी उसकी जड़ों को सींचा, उस पर इस दफा एक गुट के समर्थन और दूसरे गुट के विरोध का लेबल चस्पा था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल चुकी थीं, हालात बदल चुके थे। मगर एक सवाल राजनीति के रथियों-महारथियों से लेकर पदातिकों तक के मन में उमड़-घुमड़ रहा है कि वक्त के साथ कितना बदले हैं, मोतीलाल वोरा? इस प्रश्न का उत्तर मोतीलाल वोरा के अलावा किसी और के पास नहीं है। वोरा के फैसलों और आचरण से उत्तर मिला—वोरा ने पहले मंत्रिपरिषद् का गठन किया और फिर विधानसभा सत्र के पूर्व विस्तार। पद के बहुतेरे दावेदार टापते और हाथ मलते रह गये। विष्णु राजोरिया, भारतसिंह, महेश जोरी, मजु राय, हसनात सिद्दीकी, रामेश्वर पटेल, बंशीलाल धृतलहरे, कमला देवी, चरणदास महंत, दाऊ हनुमंत सिंह—अर्जुन सिंह के अधिकांश सिपहसालारों का एक सिरे से पत्ता साफ था।

वोरा सरकार को 'खड़ाऊं सरकार' और वोरा को 'लल्लू' निरूपित करनेवाले सकते में आ गये। लगा दिल्ली से वोरा बेदिल होकर लौटे हैं। इन्हीं दिनों बंबई व भोपाल के दो मित्र पत्रकारों से वोरा ने मजाक में कहा, "अब तो वे लोग मुझे जालिम सिंह कहने लगे हैं।" 'वे' से वोरा का तात्पर्य मोटे तौर पर अर्जुन-समर्थकों से था।

काबीने का विस्तार हुआ, तो वोरा ने एक बार फिर विरोधियों से निर्मम सलूक किया। भारत सिंह, बंशीलाल और महेश जोशी जैसे कट्टर समर्थकों को तो दूर, उन्होंने चंद्रप्रभाष शेखर जैसे सौम्य नेता को भी घास नहीं डाली। कैप्टन जयपाल सिंह को गृह एवं परिवहन विभाग एवं काबीना मंत्री का दर्जा देकर अर्जुनपरस्तों के जले पर नमक वे पहले ही छिड़क चुके थे। राज्यवर्धन सिंह (नरसिंहगढ़), नंदलालमाटा और तुलसी सिलावट (इंदौर) और विजयलक्ष्मी साधो (खरगोन) को मंत्रिपरिषद में शामिल कर वे क्रमशः दिग्विजय सिंह, अजीत जोगी और सुभाष यादव को नश्तर चुभोने से बाज नहीं आये।

पहले निर्देशित, अब निर्देशक : वोरा

वोरा या यह रूप उनके परिचितों के लिए भी नया था। उनके बदले हुए तेवर खतरनाक लग रहे थे। लगा कि वे प्रतिद्वंद्वियों की जड़ों में मट्ठा डाले बिना चैन नहीं लेंगे।

वोरा दब्बू से दबंग हो चुके थे। वोरा कब क्या कर बैठेंगे, कोई भरोसा नहीं था? मगर आगे जो घटनाएं घटी, उन्होंने लोगों को फिर से पुनर्विचार करने को बाध्य कर दिया।

दुर्बलता उभरी : अर्जुन—प्रवर्तित तेंदू पत्ता नीति पर अमल ने वोरा की स्वभावगत कमजोरी को फिर से उभार दिया। खरसिया-उपचुनाव में जीतने के बाद अर्जुन सिंह ने यह नीति तेंदू पत्ता व्यवसाय से बिचौलियों की समाप्ति के लिए तैयार की थी। सिंह की इस नीति को जहां आदिवासियों के उत्थान का क्रांतिकारी कार्यक्रम माना गया था, वहीं प्रदेश की राजनीति में सक्रिय ताकतवर बीड़ी लाबी ने इसका घोर विरोध किया था। तेंदू पत्ते के संग्रह से हर साल ठेकेदार करोड़ों रुपए कमाते थे, जबकि सरकार को सालाना साठ करोड़ रुपए की आय होती थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि सरकार अपनी खामियों से भरी मशीनरी के बल पर क्या इस नीति पर समुचित अमल कर सकेगी? अर्जुन सिंह ने अपने प्रियपात्र सांसद अजीत जोगी को इस काम में विशेष तौर पर लगाया था। सिंह अचानक पद से विदा हुए, तो अटकलों का बाजार गरम हुआ। पता नहीं वोरा नीति जारी रखेंगे या बीड़ी लाबी के दबाव में इसे पलट देंगे? प्रदेश में परमानंद पटेल, श्रवण पटेल, अरविंद पटेल, विट्ठलभाई पटेल, विधायक हाजी, सांसद डालचंद जैन, विधायक हरनाम सिंह आदि को बीड़ी लाबी के कर्णधारों में गिना जाता है। वोरा ने विट्ठलभाई को मंत्री बनाया, तो माना गया कि बीड़ी लाबी के दिन फिर गये हैं? उल्लेखनीय है कि अर्जुन सिंह पदच्युत हो चुके थे, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा थी कि तेंदू पत्ता नीति जारी रहे। सिंह ने इन्हीं दिनों बातचीत में 'माया' से कहा था कि उन्हें पद से हटाने का बीड़ी-सिंडीकेट का मंशा तो पूरा हो गया, किंतु पदत्याग के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वोरा उनके काल की अच्छी नीतियों को जारी रखेंगे। बहरहाल, गेंद अब वोरा के पाले में थी।

तेंदू पत्ता नीति को लेकर वोरा प्रारंभ में दुविधा में थे। तेंदू पत्ता नीति से खिलवाड़ सांप के बिल में हाथ डालना था। उन्होंने अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किया और इसे जारी रखने का फैसला किया। वे जानते थे कि इसे रद्द करने से विरोधियों को पूरे प्रदेश में और दिल्ली में मोर्चा खोलने का ताकतवर औजार मिल जायेगा। अतः तेंदू पत्ता नीति को जारी रखने की घोषणा के साथ उन्होंने दो और काम किये। एक तो सैकड़ों शेयर-प्रमाणपत्रों का वितरण रुकवा दिया, दूसरे, व्यापारियों से अग्रिम निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

वोरा के ये दोनों फैसले अर्जुन लाबी को नागवार गुजरे। पहला फैसला इस नाते, क्योंकि प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री के साथ में अर्जुन सिंह का चित्र भी मुद्रित था। लगे हाथ अग्रिम निविदा की नीति पर भी आपत्तियां उठायी गयीं। अर्जुन लाबी पहला मोर्चा तो हार गयी, किंतु दूसरे मोर्चे पर उनके हाथ फतह तब लगी, जब वोरा को मन-मसोसकर अग्रिम निविदाएं आमंत्रित करने विषयक फैसला रद्द करना पड़ा। समूचे प्रसंग में वोरा ने जो

साक्षात्कार/ मोतीलाल वोरा

मैं कभी किसी के आगे नहीं झुका

क्षेत्रफल के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने करीब दो दशक पहले जब दुर्ग की वार्ड मेंबरी से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तो किसी को खयाल भी न था कि वे प्रधानमंत्री के अत्यंत विश्वासपात्र होकर केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे और दो-दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव अर्जित करेंगे। वोरा आज प्रधानमंत्री की पसंद हैं, लेकिन इसके बाद भी मप्र में उनका रास्ता निष्कंटक या आसान नहीं है। संयुक्त दौरों के हश्र और उनकी विफलता ने समन्वय के उपदेशों और दावों की कलई खोल दी है। चुनाव कुछ आगे-पीछे भले ही हों, किंतु यह असंदिग्ध है कि यह चुनावी-वर्ष है। ऐसे में वोरा की जिम्मेदारियां और उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। प्रस्तुत हैं, बाहरी तौर पर निष्कंटक, किंतु अंदरूनी तौर पर चुनौतियों व संकटों से घिरे वोरा से लंबी बातचीत के अंश:

माया: ***नाटकीय परिस्थितियों में मप्र का दुबारा मुख्यमंत्री बनने का श्रेय आप किसे देते हैं?***

वोरा: *मुझे दुबारा मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय इंका आलाकमान और प्रधानमंत्रीजी को है। मैंने सदैव समर्पण भावना से कार्य करना उचित समझा है और कोशिश की है कि नेता के हर आदेश का पालन हो। मुझे पुन: मुख्यमंत्री बनाना उस विश्वास का प्रतीक है जो उन्होंने व्यक्त किया।*

माया: ***कहा जाता है कि आलाकमान केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, किंतु अर्जुन सिंह गुट के अड़ियल रवैये के कारण अंतत: आपको बतौर कंप्रोमाइज (समझौता) मुख्यमंत्री बनाया गया?***

वोरा: *इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इंका आलाकमान का निर्देश और फैसला सर्वोपरि है। भेजे गये पर्यवेक्षकों ने जो राय दी, उसी आधार पर इंका हाईकमान ने फैसला किया। मैं नहीं समझता कि किसी का रवैया अड़ियल रहा होगा।*

माया: ***फिर नये नेता के चुनाव में इतना विलंब क्यों हुआ?***

वोरा: *विलंब सभी विधायकों से चर्चा के कारण हुआ।*

माया: ***क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मप्र में पिछले चार-पांच सालों के अंतराल में गुटबाजी में काफी वृद्धि हुई है?***

वोरा: *मैंने चीजों को गुटबाजी के चश्मे से कभी नहीं देखा और न ही कभी गुटबाजी की। गुटबाजी तभी स्वागतयोग्य है, जब वह देश और प्रदेश के हित में हो।*

माया: ***तो क्या आप इससे भी इनकार करेंगे कि मप्र में इंका में अंतर्कलह है?***

वोरा: *मप्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है। बड़े दल में मतभेद होना स्वाभाविक है, मगर पार्टी में अंतर्कलह नहीं है।*

माया: ***आपको एक कमजोर प्रशासक माना जाता है और यहां तक कहा जाने लगा है कि मप्र में निर्वाचित सरकार नहीं, वरन नौकरशाही का राज है?***

वोरा: *यह निहित स्वार्थों का प्रचार है। यह सत्ता के उन दलालों का प्रचार है जो अभी तक अनियंत्रित तरीके से काम करते रहे हैं। यदि प्रदेश में नौकरशाही हावी होती, तो प्रदेशव्यापी सूखे का सामना करना कैसे संभव होता? प्रदेश में राहत कार्यों में करीब दस लाख लोग कार्यरत हैं। पांच लाख लोग तेंदू पत्ते के संग्रह में लगे हुए हैं। नौकरशाही पर अविश्वास भला क्यों और कैसे किया जाये? प्रशासन के अंगों को तो विश्वास में लेकर ही चला जायेगा।*

माया: ***इस बात में कहां तक सचाई है कि आपने इस बार मुख्यमंत्री पद अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया है?***

वोरा: *अनिच्छा का सवाल ही नहीं उठता। मैंने हाईकमान का आदेश शिरोधार्य किया। मुझे मप्र में काम करने में आनंद आता है। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्रीजी ने मुझ पर पुन: विश्वास व्यक्त किया।*

माया: ***अर्जुनसिंह के दौरों को प्राय: इस नजर से देखा जाता है कि वे आपके लिए घातक हैं। शायद इसीलिए उनके एकल दौरों पर पाबंदी लगायी गयी और सामूहिक दौरों के निर्देश दिये गये...***

वोरा: *किसी के दौरे किसी के लिए घातक नहीं होते, लेकिन जो समर्पित लोग हैं, वे स्व की छवि को उभारने के लिए नहीं, वरन् दौ से पार्टी की छवि को उभारने का प्रयत्न कर हैं। यह कहना सही नहीं है कि एकल दौरों पर प्रतिबंध लगाया गया। दौरों से मेरे राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भविष्य न किसी के दौरों से बनता है न बिगड़ता है।*

माया: ***पुराने संदर्भों पर गौर करें, तो पहले आप अर्जुन सिंह के समीप और विश्वस्त माने जाते थे, किंतु आज आप अर्जुन-विरोधी और सिंधिया के विश्वस्त माने जाते हैं। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि क्या है?***

वोरा: *मैं कभी किसी का विरोधी नहीं रहा। जिनका पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास है, उनसे मेरा कभी विरोध नहीं रहा। किन्हीं लोगों के सोचने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, कार्यपद्धति अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यदि हम समर्पण और प्रतिबद्धता से काम करते हैं, तो एक दूसरे के विरोधी नहीं माने जा सकते। रही बात विश्वस्त होने की, सो विश्वास अर्जित किये बिना कोई किसी का विश्वस्त नहीं बन सकता और विश्वास कथनी से नहीं करनी से उत्पन्न होता है। मेरी आस्था पार्टी के हितों के तहत संबंधों को गाढ़ा करने में है।*

माया: ***अर्जुन सिंह ने अपने दौरों का प्रयोजन राज्य में सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष निरूपित किया था। कुछ लोगों की धारणा है कि आज सांप्रदायिकता के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष छेड़ना अपरिहार्य है। इस बारे में आपकी क्या धारणा है?***

वोरा: *सांप्रदायिकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने सदैव पहलकदमी की है। आज की पहली आवश्यकता भ्रष्टाचार को खतम करने की है। भ्रष्टाचार को तत्काल खतम तो नहीं कम जरूर किया जा सकता है। मेरी यह भी मान्यता है कि शासन में बैठे व्यक्ति की छवि साफ और उजली होनी चाहिए।*

माया: ***राजीव गांधी ने मुंबई अधिवेशन में सत्ता के दलालों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया था। क्या मप्र में सत्ता के दलाल अभी भी सक्रिय हैं?***

वोरा: *राजीवजी ने जो बात कही थी, उसी आधार पर मप्र में मुहिम शुरू हुई है। सत्ता दलाल दरअसल वे हैं जो सत्ता-सुख भोगने के बाद इंका की नीतियों व फैसलों की मुंहफट होकर आलोचना करते हैं।*

माया: ***मप्र में सत्ता के दलालों में आप किन्हें गिनेंगे?***

वोरा: *ऐसे लोगों को प्रदेश व देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। इनके नामों के*

उल्लेख की जरूरत नहीं। इन्होंने सत्ता कैसे पायी और उसका कितना दुरुपयोग किया, यह किसी से छिपा नहीं है।

माया: मप्र में नेतृत्व-परिवर्तन में विधायकों से अहम भूमिका सांसदों ने निभायी थी। अतः माना यह जाता है कि आपकी सरकार विधायकों के बजाय दिल्ली में सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है...

वोरा: सरकार को विधायकों व सांसदों का एक समान समर्थन प्राप्त है। हाईकमान के निर्देशन पर विधायकों ने मुझे सर्वसम्मति से चुना था।

माया: क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ने अर्जुन सिंह और आपको मतभेद भुलाकर एक साथ चलने को कहा है?

वोरा: प्रधानमंत्रीजी ने एकसाथ चलने और एकजुटता के स्पष्ट निर्देश दिये हैं। मेरी पुरजोर कोशिश है कि समुचित तालमेल बना रहे।

माया: चुरहट लाटरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भिन्न-भिन्न व्याख्याएं की जा रही हैं। फैसले पर आप क्या कहेंगे?

वोरा: कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फैसला अपने आप में स्पष्ट है।

माया: इंका की एक विधायक का कहना है कि मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह की भांति एक भी बड़ा और क्रांतिकारी कार्यक्रम देने में विफल रहे हैं। इस टिप्पणी के बारे में आपका क्या कहना है?

वोरा: मैं नहीं समझता कि जिन विधायक की बात आप कह रहे हैं, उनका कहना सही है। 'आपकी सरकार, आपके द्वार' क्या जनता से जुड़ने का बड़ा और क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं है? अर्जुन सिंह ने जो कार्यक्रम शुरू किये, वे पार्टी-नीतियों के तहत शुरू किये गये उपयुक्त कार्यक्रम थे। वस्तुतः कार्यक्रमों की तुलना परिणामों को देखकर करनी चाहिए। 'आपकी सरकार, आपके द्वार' को जबर्दस्त 'रिस्पांस' मिला है।

माया: तेंदू पत्ते की अग्रिम निविदाओं को निरस्त करने के मामले में कहा जा रहा है कि आप दबाव के आगे झुक गये?

वोरा: मैं दबाव के आगे कभी नहीं झुका और न ही झुकने का प्रश्न उठता है। तेंदू पत्तों के बारे में जो भी निर्णय लिया गया, वह प्रदेश के हित में लिया गया।

माया: इंका के कुछ विधायकों ने ग्वालियर राजघराने से संबद्ध ट्रस्टों की जांच की मांग की है। इस बारे में राजमाता सिंधिया का एक पत्र आपको मिला होगा। क्या आपको लगता है कि विधायकों की मांग राजनीति-प्रेरित है? आपने इस बारे में क्या फैसला किया है?

वोरा: राजमाता का एक पत्र मुझे मिला है, जिसका मैंने जवाब दे दिया है। विधायकों की मांग मुझे राजनीति-प्रेरित प्रतीत होती है। ट्रस्टों की जांच की मांग तब की गयी है, जब संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। फिलहाल, मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूं और जानकारी मिलने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकूंगा।

माया: दुर्ग उपचुनाव में आप भारी मतों से विजयी रहे, किंतु यह भी सच है कि आपके मतों में वृद्धि नहीं हुई और शिवसेना के बिसे यादव को बीस हजार से अधिक मत मिले। क्या यह आम मतदाताओं में शिवसेना के बढ़ते असर का द्योतक नहीं है?

वोरा: पहली बात तो यह कि उम्मीदवार शिवसेना का नहीं था। भाजपा के नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि बिसे यादव तो हमारे उम्मीदवार थे, हमने उन्हें नगरपालिका चुनाव में टिकट दिया था। उन्हें बीस हजार से अधिक मत मिलने का आशय यह नहीं है कि सांप्रदायिक शक्तियों की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस-इ के मतों में भी वृद्धि हुई है।

माया: मप्र में कांग्रेस-इ में अंतर्कलह और प्रशासन के बिगड़े ढर्रे के कारण भाजपा अगली सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। क्या उसके मनसूबे पूरे होंगे?

वोरा: भाजपा के मनसूबे पूरे होने की स्थिति मप्र में कतई नहीं है। वजह यह कि भाजपा के पास थोथे नारेभर हैं। सर्वहारा वर्ग को भाजपा पर किंचित विश्वास नहीं है। भाजपा की गतिविधियों से ऐसे तत्वों को पोषण व बल मिलता है जो सामंती व सांप्रदायिक हैं।

माया: क्या कारण है कि इस बार आप फिर काकस से घिर गये हैं?

वोरा: मैं किसी काकस के घेरे में न रह सकता हूं और न रह रहा हूं।

माया: आपकी छवि एक भले मानुष की है, न कि एक चतुर चालाक कुटिल राजनेता की। इस छवि के बरक्स आप क्या महसूस करते हैं?

वोरा: कुटिलता राजनेता का गुण नहीं हो सकती। यदि मुझमें कुटिलता नहीं है, तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरे मानने या न मानने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं?

माया: क्या आप अपने पुत्र को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं?

वोरा: राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाये नहीं जाते। उन्हें अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है और अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है।

—सु०स०

ढुलमुल रवैया अख्तियार किया था, उसने वन मंत्री डा० कन्हैयालाल शर्मा को भी विक्षुब्ध किया। इस प्रसंग ने यह अनायास उजागर कर दिया कि वोरा ने दबावों के आगे झुकने की लीक पूरी तौर पर छोड़ी नहीं है।

विफलताएं: भोपाल और दिल्ली में यह कहा जाता है कि वोरा बहुसंख्य विधायकों के विपरीत बहुसंख्य सांसदों की पसंद से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अर्जुन सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह शुक्ल और सेठी गुट के विधायक फोड़े थे और अपनी जड़ें जमाई थीं, उस तरह का खेल खेलने में वोरा नितांत विफल रहे। एक इंका विधायक (जो सरकारी उपक्रम के अध्यक्ष भी हैं) ने इसके कारणों की मीमांसा करते हुए 'माया' से कहा, "वोराजी के प्रतिशोध की सीमाएं हैं। वे इस लक्ष्मणरेखा को कभी पार नहीं करते।" विधायक की यह टिप्पणी वोराजी के बरसों के आचरण के विश्लेषण से उपजी है। अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा में यह फर्क मायने रखता है कि सत्ता-प्रमुख के सिंहासन पर वोरा की उपस्थिति नेताओं और नौकरशाहों में भय और धुकधुकी पैदा नहीं करती। जबकि अर्जुन सिंह के तेवरों और आकस्मिक स्तब्धकारी फैसलों से बड़े-बड़े नेताओं और मंजे हुए नौकरशाहों तक में धुकधुकी मची रहती थी। इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि वोरा के हाथ में राजदंड होने के बावजूद लोगों में उसका भय पैदा नहीं हुआ। पिछले विधानसभा सत्र को ही लें। ऐन बजट सत्र के दौरान कई विधायक पांच जून को इंदौर में अर्जुन के दौरे में शरीक होने चले गये। लिहाजा, विधानसभा में शक्तिपरीक्षण में सरकार धराशायी होते-होते बची।

तुरत दान, महा कल्याण: एक अपंग को सहायता राशि देते हुए वोरा

फाकस पुनः सक्रिय : चहेते माणक अग्रवाल से वोरा की मंत्रणा

अगल-बगल नहीं, आमने-सामने : वोरा और अर्जुन सिंह

हालांकि वोरा के सत्तासीन होते ही अनेक सरकारी निगमों के अध्यक्षों में यह भय व्याप्त हो गया था कि इतर निष्ठा के चलते वोरा कहीं उन्हें चलता न कर दें। वोरा का प्रारंभिक तेवर उनमें आशका और भय का संचार करने को पर्याप्त था। वोरा ने भी मामले की नजाकत और वक्त के तकाजे को समझा और निगमों की समीक्षा के लिए पूर्व मुख्यसचिव केसीएस आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त कर डाली। आम धारणा थी कि आचार्य कमेटी की रपट कई निगमों के अध्यक्षों की विदाई का बहाना बनेगी। मगर आचार्य साहब मंथर गति से चले। नतीजतन नागेंद्र सिंह, मुकेश नायक, केएस ठाकुर, प्रेमनारायण मिश्र, हरबंस सिंह आदि अभी भी यथावत पदासीन हैं।

खामियां : एक वरिष्ठ आईएएस ने 'माया' से कहा, "वोरा स्टंटबाजी में माहिर नहीं हैं। मौकों को वे अर्जुन सिंह की तरह भुना नहीं पाते हैं। वोरा व अर्जुन सिंह में यही अंतर है। अखबारों के जरिये राजनीति का 'डम-डम डिगा-डिगा' खेल भी वोरा, सिंह की तरह नहीं खेल पाते। वोरा की असली ताकत है, उनकी ईमानदारी, निष्कपटता और गुटों से अलग चलने की प्रवृत्ति। बाकी बातों की बातें करें, तो वोरा स्टंटबाजी व वैभवसिक्त प्रचार आदि में कहीं-न-कहीं सिंह से पिछड जाते हैं।

वोरा को दुबारा मुख्यमंत्री बने सौ दिन कभी के बीत चुके हैं। प्रदेश के वे सर्वाधिक मेहनती मुख्यमंत्री हैं। तड़के से लेकर रात एक-डेढ बजे तक काम करना उनकी आदत और दिनचर्या में शुमार है। इसके बाद भी वे नौकरशाही को उस ढांचे में नहीं ढाल सके हैं, जिससे लोकहित के वांछित और अपेक्षित नतीजे निकलें। प्रशासन में चुस्ती आज भी नदारद है। फाइलें कच्छप-गति से ही सरकती हैं और लालफीतों की गाठें मजबूत हुई हैं। 'आपकी सरकार, आपके द्वार' से आशाएं बंधी हैं, परंतु यह अस्थायी उपक्रम है। इसकी क्या गारंटी कि पंद्रह अगस्त के बाद सरकार व जनता की देहरी के बीच फासला फिर से बढ़ नहीं जायेगा?

वोरा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान वे आज तक नहीं कर सके। उनका भलामानुष होना, लगता है, इसमें भी आड़े आता है। न वे रायगढ़ व अन्यत्र के सफेदपोश जंगलचोरों के खिलाफ कड़े कदम उठा सके और न ही सहकारिता माफिया की जड़ों पर चोट कर सके। वनों की हरियाली को नोटों व सोने के बिस्कुटों की शक्ल में अपनी तिजोरियों में कैद करनेवाले शक्तिशाली लोगों के बारे में रायगढ़ के कलेक्टर की रपट आज भी बल्लभ-भवन में कहीं धूल खा रही होगी। खबर है कि अब वोरा ने सहकारिता में आरक्षण का समावेश करने का मन बनाया है। देखना है कि वे अपने मन की कहां तक कर पाते हैं? यदि वे सफल हो गये, तो सहकारिता के ढांचे में आरक्षण के रास्ते प्रविष्ट नया तबका उन्हें सहकारिता माफिया के खिलाफ जंग के लिए जमीन मुहैया करेगा।

समन्वय : ऐसा प्रतीत होता है कि वोरा के इरादों को अर्जुन सिंह और उनकी बिरादरी ने समय पर भांप लिया था और समय रहते ही उनके काट की रणनीति तैयार कर ली थी। वोरा का कहर अर्जुन-शिविर पर टूटता, इसके पहले ही अर्जुन सिंह ने एकल दौरे की घोषणा कर रणभेरी फूंक दी। इन पर रोक लगाने के लिए आलाकमान को प्रदेश इंकाध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर के जरिये संयुक्त दौरों की घोषणा करानी पड़ी। संयुक्त दौरों की घोषणा को अर्जुन सिंह ने हाथोहाथ लिया। चतुर सुजान अर्जुन की ताकत व चतुराई को वोरा समझ नहीं सके। अर्जुन सिंह के दूत दिल्ली में वसंत साठे और आला नेताओं के इर्दगिर्द सक्रिय थे। पहली कोशिश थी कि ताकत को बिखरने व क्षय होने से बचाया जाये। वोरा के खिलाफ मुहिम से प्रधानमंत्री की नाराजगी का भय था। एक ही रास्ता था कि वोरा को आक्रामक होने से रोका जाये। ऐसे में दिल्ली के समन्वय के सूत्र ने मप्र में अवश्यंभावी द्वंद्व को तात्कालिक तौर पर टाल दिया। अर्जुन सिंह ने वोरा के साथ रायपुर, भोपाल और इंदौर में संयुक्त दौरों में भाग लिया। मुख्यसचिव की उपस्थिति में सिंह व वोरा के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर लंबी चर्चा हुई और वोरा व सिंह दिल्ली में मई में एक-दूजे के भोज में शरीक हुए।

राज्यसभा चुनाव : यह सच है कि वोरा अपनों के लिए बहुत दूर तक नहीं लड़ते। निर्गुट राजनीति से अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ पाया है, उससे उनकी गुटीय राजनीति में अधिक रुचि नहीं रही। आज भी उनके गुट में सिंधिया के समर्थकों व शुक्ल बंधुओं के पुराने समर्थकों की तादाद महत्वपूर्ण है। खबर है घंसौर की उर्मिला सिंह वोरा के कैंप में आने को लालायित थीं, मगर लोनिवि मंत्री कुमारी विमला वर्मा ने न जाने क्या 'तीन-पांच' किया कि वे उलटे पांव सिंह कैंप में लौट गयीं। इसी भांति वोरा से चंद्रप्रभाष शेखर की कई मुलाकातें हुईं। सौम्य शेखर कभी अर्जुन सिंह की किचेन कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे। अर्जुन सरकार में रहते हुए भी उनका वोरा से कभी वैर नहीं रहा। वे राजोरिया व भारत सिंह जैसे कट्टर अर्जुन समर्थक व महेश जोशी जैसे मुंहफट नेता भी नहीं हैं। यदि वोरा उन्हें मंत्री बनाते, तो वे कृतज्ञता के बोझ से दबे रहते। ऐसा हो भी जाता, किंतु सलाहकारों ने मति फेर दी। लिहाजा शेखर आज भी काबीने के कूचे से बाहर हैं। पिछले राज्यसभा चुनाव का प्रसंग आज भी लोग भूले नहीं हैं, जब आरोपों से बिंधे अजीत जोगी और बालाघाट की अल्पज्ञान नेत्री सईदा खातून टिकट पा गयी थीं और वोरा की सूची जेब में धरी रह गयी थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। डा० भंवरसिंह पोर्ते वोरा की पहली पसंद थे, लेकिन वोरा उन्हें टिकट दिलाने में

विफल रहे, जबकि यह माना जा रहा था कि इस मर्तबा टिकट उसे ही मिलेगा, जिसे वोरा चाहेंगे। राज्यसभा की इस सीट के लिए वोरा की पसंद का महत्व इसलिए ज्यादा था; क्योंकि यह सीट उनके इस्तीफे से रिक्त हुई थी। किंतु बैतूल से निर्वाचित सांसद एवं सितारा खिलाड़ी असलम शेर खां का साथ देने के कारण गुफरान के कोपभाजन बन चुके वोरा अपने रिक्त स्थान पर अपने पसंदीदा आदमी को नहीं ला सके और दोनों गुटों के सिपहसालारों को धता बताते हुए गुफरान धड़ल्ले से राज्यसभा में पहुंच गये।

आरोप : ऐसा नहीं है कि मोतीलाल वोरा आरोपों से बिंधे नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश भाजपा के नेता सुंदरलाल पटवा का कहना है कि वोरा सरकार में भ्रष्टाचारी और अपराधी भरे हुए हैं। इधर वोरा पर 'काकस' से घिरे होने का आरोप फिर से लगने लगा है। वोरा के पिछले मुख्यमंत्रित्वकाल में परछाई की भांति उनके साथ रहनेवाले माणक अग्रवाल इस बार वोरा के प्रारंभिक सौ दिनों में खामोश रहने के बाद फिर से सक्रिय हो गये हैं। लंबी तनातनी के बाद माणक और रसूल अहमद सिद्दीकी में पुनः सुलह हो गयी है। दुर्ग की 'त्रयी'—भजनसिंह निरंकारी, शंकरलाल ताम्रकार और रामानुजलाल यादव—आज भी वोरा के 'नाक के बाल' हैं। पूत के पांव पालने के लिहाज से अरुण वोरा को मोतीलाल वोरा का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है।

राजीव के काफिले में वोरा

अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ बयानबाजी करे या उनके विवेक पर उंगली उठाये। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पशुधन मंत्री ने स्वस्थ परंपराओं को तिलांजलि देकर गत दिनों बयान दिया कि राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल के बस्तर दौरे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दुर्ग प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वोरा ने उनकी उपेक्षा की। इस पर मुख्यमंत्री ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, किंतु पोटाई के निर्वाचन क्षेत्र भानुप्रतापपुर के पांचों सरपंचों एवं विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से मांग कर डाली कि गंगा पोटाई को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाया जाये।

लोगों के बयानों व कृत्यों पर वोरा चुप्पी भले ही साधें, लेकिन विरोधी खेमा खंदकें खोदने और रसद बारूद इकट्ठा करने के काम में अहर्निश लगा हुआ है। सिंधिया राजघराने के ट्रस्टों की जांच की मांग इसी अभियान की सुनियोजित कड़ी है। 'माया' ने विधायकों से चर्चा में पाया कि आमतौर पर विधायक वोरा को भला, लेकिन दुर्बल प्रशासक मानते हैं। पूर्वमंत्री श्रीमती मंजुराय ने 'माया' से कहा, "वोरा अर्जुन सिंह की भांति बड़े और क्रांतिकारी कार्यक्रम एवं नीतियां देने में विफल रहे हैं। अपने फैसलों व कार्यक्रमों की वजह से अर्जुन सिंह का आज भी प्रदेश में व्यापक जनाधार है।" श्रीमती राय का यह कथन एक प्रकार से एक शिविर के विधायकों की सामूहिक राय की अभिव्यक्ति है। वोरा-विरोधी शिविर समन्वय अभियान से आश्वस्त कम, आशान्वित ज्यादा है। जैसाकि पूर्वमंत्री चरणदास महंत ने कहा, "मैं आशान्वित हूं कि अर्जुन सिंह और वोरा में समन्वय की स्थिति बनेगी और दोनों की सम्मिलित शक्ति का उपयोग आगामी चुनाव में पार्टी-हित में होगा।"

ताकत : कुछ भी हो पार्टी के भीतर इन स्थितियों और चतुर व ताकतवर विरोधियों के जमावड़े के बावजूद वोरा के पक्ष में अनेक ऐसी बातें हैं, जो उन्हें राजनीति में लंबी पारी खेलने का ताब देती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वोरा ने दुर्ग में उपचुनाव डंके की चोट पर लड़ा और ऐसे समय में करीब ५५ हजार मतों के प्रचंड बहुमत से विजयी हुए, जबकि भाजपा प्रदेश में अगली सरकार बनाने के मंसूबे बांध रही थी। मजे की बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी व जनता दल को दुर्ग में वोरा से लड़ने के लिए सुयोग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। दिल्ली में वोरा की यह जीत इसलिए मायने रखती है, क्योंकि अर्जुन सिंह जैसे चतुर सुजान के लिए खरसिया उपचुनाव 'वाटरलू' बनते-बनते बचा था। उपचुनावों का वृत्तांत देखें, तो वोरा के काल में कांग्रेस-इ ने अपेक्षाकृत अधिक उपचुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वोरा इस नाते विशेष प्रिय हैं, क्योंकि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। मई और जून के केवल दो माह में प्रधानमंत्री की मप्र की एक-के-बाद-एक चार यात्राएं वोरा के प्रति उनका अनुराग दर्शाती हैं। १६ जून को जब प्रधानमंत्री के न्यौते पर समस्त इंका विधायक दिल्ली पहुंचे, तो अगले दिन वोरा ने दोपहर का भोज दिया। इसके पूर्व १६ जून को अर्जुन सिंह रात्रिभोज दे चुके थे। राजीव गांधी केवल वोरा के भोज में शरीक ही नहीं हुए, वरन वहां करीब घंटाभर रहे। वैसे, सौजन्यता में वोरा का कोई सानी नहीं है। आडंबर और दर्प से वे परे हैं। दिल्ली में अपनी ओर से रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया के यहां चले जाना और समन्वय की नीति के तहत भोपाल में बातचीत के लिए बगैर ना-नुकर के अर्जुन सिंह के बंगले चले जाना, वोरा के ही बस की बात है। इस साल तबादलों पर रोक लगाकर उन्होंने दलालों और बिचौलियों के हितों पर सीधी चोट की है। सिंधिया घराने के ट्रस्टों की जांच की मांग, तेंदू पत्तों के लिए बोरों की सप्लाई में कथित अनियमितताएं और बैतूल के आप्रवासी उद्योगपति सैम वर्मा के निजी विमान को शासकीय हैंगर से हटाने के मामलों में उनके निर्णय ऐसे रहे हैं, जो बताते हैं कि वक्त के साथ वोरा बदले हैं। वे पहले जैसे दब्बू नहीं रह गये हैं, लेकिन उतने दबंग भी नहीं है, जितना उनके होने की संभावना जनवरी-फरवरी में उपजी थी। फिलहाल, दबंग न हो पाना, शायद मोतीलाल वोरा की राजनीतिक विवशता है, जो पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों, प्रादेशिक राजनीति के जटिल समीकरणों और दिल्ली के निर्देशों की कोख से जन्मी है। 'रिमोट-कंट्रोल' की राजनीति के इस अलबेले दौर में वोरा इस विवशता से कब उबरेंगे, कहा नहीं जा सकता?

—सुधीर सक्सेना

राजनीति का अपराधीकरण

चुनाव में सहयोग: इलाहाबाद उपचुनाव में भुक्खल महाराज (दायें सबसे ऊपर)

आजकल चुनाव जीतने के लिए मात्र धन की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लाठी-बंदूक की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती समझा जाता है, वे राजनेताओं के प्रिय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुख्यात लोगों को प्रश्रय केवल सत्तारूढ़ दल से ही मिलता है, विपक्ष भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। दूसरों को चुनाव जिताने की 'क्षमता' रखनेवाले ये बाहुबली स्वयं भी राजनीति में उतरने लगे हैं और आपराधिक आरोपों से घिरे व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर भी विराजमान हैं। इस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण तेजी से जारी है। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में यह प्रक्रिया घातक रूप ले सकती है?

सातवें दशक के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष चंद्रभानु गुप्त ने एक बार विधान सभा में चिंता जाहिर की थी कि राजनीतिक दल अपराधकर्मियों को संरक्षण दे रहे हैं। सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल बीके नेहरू ने तो यहां तक कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विधायकों में से बहुत से ऐसे हैं जो अपराधकर्मी थे और जिन पर आपराधिक मुकदमे चले। हाल ही उत्तर प्रदेश के एक वयोवृद्ध राजनेता ने कहा, "पहले राजनेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वही राजनेता असरदार बन पाता है, जिसे अधिकाधिक अपराधियों का संरक्षण प्राप्त होता है।" दरअसल राजनीति के अपराधीकरण की यही प्रक्रिया रही। पहले कुछ राजनेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण अपराधियों को संरक्षण दिया और उनकी मदद ली। अपराधियों को भी अपने और अवैध धंधों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। दोनों की जरूरतों ने दोनों को परस्पर पूरक बना दिया, लेकिन उसके बाद थोड़े ही अरसे में सारा मामला उलट गया। अपराधियों को भी राजनीति का चस्का लग गया और वे खुद राजनेता बनने लगे और आज हालत यह है कि राजनीति के लिए अपराधियों की छत्रछाया एक अपरिहार्य जरूरत बन चुकी है।

भयभीत विधायक: ३ मार्च, १९८१ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह सवाल पूछा गया था कि इस सदन में ऐसे कितने सदस्य बैठे हैं, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा कितने ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर हैं। उठते-बैठते अपराधकर्मियों को समाप्त करने का संकल्प दोहरानेवाले तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय तब बच निकलने की कोशिश की थी। उनका जवाब था कि जानकारी इकट्ठा करने में जितना समय और साधन नष्ट होगा, उसके मुकाबले लाभ बहुत कम होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह सबकुछ जानते हुए भी इस कड़वे सच को छुपाना चाहते थे कि सदन के आधे से अधिक विधायक अपनी जान के लिए खतरा महसूस करते हैं और सरकार ने उनके लिए अंगरक्षक की व्यवस्था की है। तब सदन में ही प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के ६५ विधायकों के विरुद्ध पुलिस में अपराधकर्मी होना दर्ज है और इसकी जांच होनी चाहिए।

फरवरी, १९८१ में बेहमई में सामूहिक हत्याकांड हुआ था। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने वहां मुलायम सिंह यादव को दस हथियारबंद व्यक्तियों के साथ मौजूद देखा था। मुलायम सिंह खुद कारबाइन लटकाये घूम रहे थे। जब उनसे पूछा गया था कि इन सबकी क्या जरूरत? उनका जवाब था, "जानते नहीं? बलराम सिंह गैंग पाले हैं। मुझे बलराम सिंह से खतरा है।" पास खड़े एक नेता ने उसी समय धीरे-से टिप्पणी की थी, "हां बलराम सिंह के गैंग की चर्चा मुलायम सिंह कर रहे हैं और उनका अपना 'गैंग' सामने है।" आज दोनों क्रमश: प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष हैं और सिर पर खड़े आमचुनाव में दोनों के सिर पर अपनी-अपनी पार्टी को विजयी बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन आपराधिक छवि के लोग देश के इन पक्ष-विपक्ष के कर्णधारों के आगे-पीछे क्यों नजर आते हैं? लखनऊ के एक बदनाम छवि के अरुण शंकर शुक्ल उर्फ अन्ना को मंच पर बिठाने और सार्वजनिक रूप से उसकी थैली स्वीकार करने पर जब मुलायम सिंह यादव की तीखी आलोचना हुई, तो मुलायम सिंह ने बड़ा रोचक जवाब दिया था, "अपराधकर्मियों के हृदय-परिवर्तन का ठेका क्या अकेले कांग्रेस ने ले रखा है?"

यादव भी पीछे नहीं: मुलायम सिंह यादव 'अन्ना' से थैली लेने के लिए बदनाम हुए, तो बलराम सिंह यादव पर भी आरोप लगा कि उन्होंने बाराबंकी के कुख्यात रंजीत बहादुर श्रीवास्तव से न केवल २१ हजार रुपए की थैली भेंट स्वरूप ली, बल्कि उन्हें विधायक सुरेंद्र अवस्थी की सिफारिश पर कांग्रेस में समारोहपूर्वक शामिल भी किया। रंजीत बहादुर को जिले के व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन जब इस पर हल्ला मचा, तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी। इसके कुछ दिनों बाद ही रंजीत बहादुर को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रंजीत बहादुर के व्यक्तिगत रसूख का आलम यह था कि उनकी गिरफ्तारी के २४ घंटों के अंदर उन पुलिस अधीक्षक ब्रजलाल का वहां से तबादला हो गया जो अपनी ईमानदारी, सूझबूझ और बहादुरी की वजह से खतरनाक तस्करों को पकड़ने के लिए बाराबंकी भेजे

बहुचर्चित तस्वीर: प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बायें नाजिर अली

सत्ता के साथ: बलराम सिंह यादव

गये थे।

इटावा के रामबहादुर तिवारी तथा २६ अन्य श्रमिक नेताओं ने १९८१ में मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर बलराम सिंह यादव पर कई व्यक्तियों की हत्या कराने और डाकू गिरोहों को संरक्षण देने के आरोप लगाये थे। उनमें कुछ आरोप इस प्रकार थे—जसवंत नगर पुलिस द्वारा जब ककरई गांव के डकैत जगदीश को बंदूक सहित गिरफ्तार किया गया था, तब बलराम सिंह यादव स्वयं थाने गये और उसे छुड़ा लाये थे। मैनपुरी पुलिस ने इनामी डकैत गिरीश और सोबरन को गिरफ्तार किया था, तो बलराम सिंह यादव ने मैनपुरी पुलिस अधीक्षक को फोन करके निर्देश दिया था कि इन डाकुओं को तंग न किया जाये। बलराम सिंह यादव उन दिनों सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री थे। इन तमाम आरोपों के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बलराम सिंह यादव को अपनी स्थिति स्पष्ट करने या इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। लेकिन यादव की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि, न तो उन्होंने सफाई दी और न ही इस्तीफा दिया, अलबत्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह को डकैतों के सफाये की अधूरी साध लिये बड़े बेआबरू होकर मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा।

हर कहीं अपराधी: अब हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसे अनेक असरदार राजनेता हैं, जिनका या तो खुद आपराधिक रिकार्ड है या फिर उन पर सड़क से लेकर सदन तक में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। चंबल के बीहड़ों और बुंदेलखण्ड के पठारी जंगलों के क्षेत्रीय जिलों के नेताओं पर अकसर डकैतों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, तो नेपाल से सटे जिलों में तस्करों और माफिया सरगनाओं की गतिविधियां अपने राजनीतिक रहनुमाओं के साये में जारी हैं। लोकतंत्र की बुनियाद कहे जानेवाले पंचायती और स्थानीय निकाय के चुनाव में इस वर्ष कथित अपराधियों की जीत ने राजनीति के अपराधीकरण का पूरा खाका ही खींचकर रख दिया है। इन चुनावों में तो उम्मीदवारों ने एक लाख से लेकर दस लाख रुपए तक खर्च किये। सीतापुर, बांदा आदि क्षेत्रों में जहां चर्चित अपराधकर्मी अध्यक्ष पद के चुनाव में खडे थे, वहां उनके मुकाबले खड़े होने का साहस कोई नहीं बटोर सका। वाराणसी जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सुधाकर पाण्डेय, लोकपति त्रिपाठी और उनकी पत्नी चंद्रा त्रिपाठी का समर्थन मिलने के बावजूद शराब के ठेकेदार जवाहरलाल से हार गये। धनबल और भुजबल से चुनाव जीतने की यही कहानी बांदा जिले में भी दोहरायी गयी। बबेरू ब्लाक में इस इलाके का चर्चित डकैत गया कुर्मी ब्लाक प्रमुख तो चुना ही गया, साथ ही उसके पांच साथी भी विभिन्न ब्लाकों में चुनाव जीते। पहाड़ी ब्लाक में अपराध जगत से जुड़े हीरा पाण्डेय ब्लाक प्रमुख बन गये। ओमप्रकाश गुप्त का नाम कई अपराधों में दर्ज है। वे रासुका में बंद रहे हैं, लेकिन आज वे सीतापुर नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व० वीरबहादुर सिंह के भाई गुलाब सिंह का भी गोरखपुर में आतंक है। आज वे न केवल गोरखपुर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, बल्कि जिला परिषद अध्यक्ष संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित हैं। गोरखपुर जिले में ही 'माफिया' के रूप में चर्चित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने अपने-अपने आदमियों को चुनाव लड़वाया और जिताया।

अब हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसे अनेक असरदार राजनेता हैं, जिनका या तो खुद आपराधिक रिकार्ड है या फिर उन पर सड़क से लेकर सदन तक में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

जेल से चुनाव: पुलिस के आपराधिक रिकार्ड में हरिशंकर तिवारी के कारनामे हिस्ट्रीशीट नंबर ४९-ए और वीरेंद्र प्रताप शाही के कारनामे हिस्ट्रीशीट नं० ४२-ए पर दर्ज हैं। १९८१ में शाही गोरखपुर के लक्ष्मीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने, तो १९८५ का विधानसभा चुनाव भी वे इसी क्षेत्र से जीते। इस चुनाव की खासियत यह थी कि न केवल शाही बल्कि हरिशंकर तिवारी (चिल्लूपार-गोरखपुर) राजबहादुर (जौनपुर) और रमाकांत यादव (आजमगढ़)—ये चारों ऐसे बाहुबली प्रत्याशी थे जो चुनाव-प्रचार के दिनों और मतदान के समय जेल में थे, लेकिन अपनी दहशतशुदा लोकप्रियता के बल पर वे धड़ल्ले से चुनाव जीत गये थे।

विधानसभा चुनावों में ही नहीं, बल्कि गत वर्ष हुए इलाहाबाद उपचुनाव में तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शास्त्री दोनों की ओर से कुख्यात लोगों का खुला समर्थन प्राप्त किया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में यदि बंबई के तस्कर-सरदार हाजी मस्तान की फौज ने मोर्चा बांधा था, तो कांग्रेस ने जिन बाहुबली की मदद ली थी, उन्होंने ही बाद में सारे मामले का ऐसा भंडाफोड़ किया कि कांग्रेसी नेता और प्रशासन दोनों सकते में आ गये। भुक्खल महाराज के नाम से चर्चित वशिष्ठ नारायण करवारिया के अनुसार, "मेरे विरुद्ध रासुका के तहत गिरफ्तारी के आदेश ३१ मार्च, १९८८ को जारी हुए थे, जिसके विरुद्ध मैंने उच्चन्यायालय में याचिका दायर की थी जो ३१ मई को रद्द हो गयी। उन्ही दिनों इलाहाबाद उपचुनाव की घोषणा हुई। वीरबहादुर सिंह इस चुनाव में मेरा समर्थन चाहते थे। मैंने शर्त रखी कि मेरे विरुद्ध चल रहे या दर्ज सारे मामले हटा लिये जायें। वीरबहादुर सिंह राजी हो गये और सौदा पट गया।" उसके बाद वे कांग्रेस के चुनाव प्रचार में अपने ढंग से जुट गये और जनसभाओं में वे वीरबहादुर सिंह तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ

मंचों पर बैठने लगे। अपनी बात के समर्थन में भुक्खल महाराज ऐसी जनसभाओं के मंचों के चित्र दिखाते हैं। दरअसल, यह रहस्योद्घाटन स्वयं भुक्खल महाराज को ही इसलिए करना पड़ा, क्योंकि सुनील शास्त्री के हार जाने के बाद रासुका के तहत उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुहिम फिर से शुरू हो गयी थी। भुक्खल महाराज का कहना था कि उनके खिलाफ रासुका खतम कर दिया गया था, जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ और भुक्खल महाराज फरार थे। लेकिन भुक्खल के वकील का तर्क है कि यदि मेरा मुवक्किल फरार था, तो वह मुख्यमंत्री के साथ कैसे मौजूद रहा? रोचक तथ्य यह है कि भुक्खल ने यह रहस्योद्घाटन अदालत में किया है। अब प्रदेश सरकार को भय है कि यदि इस मामले की सुनवाई हुई, तो चुनाव में अपराधियों का इस्तेमाल करने और उन्हें संरक्षण देने की पोल तो खुलेगी ही, साथ ही कांग्रेस-इ के कई बड़े नेताओं को रासुका अपराधी को छिपाये रखने के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा २१२ के अंतर्गत सजा भी हो सकती है।

मुलायम सिंह यादव

शिवनाथ सिंह कुशवाहा

१७ मई, १९८४ को दारुलशफा (विधायक निवास) में शाहजहांपुर के विधायक नाजिर अली के कमरे (नंबर-५०) से २० किलो हेरोइन पाउडर पकड़ा गया। इस घटना के बाद नाजिर अली को कांग्रेस से निकाल दिया गया, लेकिन हाल ही उनके साथ जनता दल के नेताओं के एक चित्र को लेकर जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी नेताओं और तस्करों के रिश्तों का प्रचार किया गया, तो विपक्ष की ओर से भी ऐसे चित्र प्रचारित किये गये, जिनमें नाजिर अली राजीव गांधी के साथ खड़े दिखायी दे रहे हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि अपराधी तत्वों का सहयोग लेने में पक्ष-विपक्ष में से कोई किसी से कम नहीं है। बस्ती जिले से लोकदल के वर्तमान विधायक सुखपाल पाण्डेय के घर से बुंदेलखण्ड के नामी डकैत सूरजभान की गिरफ्तारी हुई थी, तो प्रदेश के एक पूर्व राज्यमंत्री और कांग्रेस के वर्तमान महासचिव मुंशीलाल चमार की निजी कारबाइन नं० २६८१-६६८ गोलियों सहित मैनपुरी के कुख्यात डाकू ब्रजवासी गिरोह के एक सदस्य के पास से बरामद हुई थी।

हत्याओं का दौर: अपराधियों और राजनेताओं के गठजोड़ से जो कुछ भी होगा, वह अपराध ही होगा। जाने कितने राजनेता इसी के चलते मौत के घाट उतर गये। बदायूं के विधायक शिवराज सिंह और गोरखपुर के रवींद्र सिंह की हत्या की यही वजह थी कि दोनों अपराधकर्मियों से संबद्ध थे। रवींद्र सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही गिरोह के थे। शाही के विरोधी गिरोह ने उन्हें गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दिनदहाड़े गोली मार दी थी। फरवरी, १९८१ में जब तत्कालीन विधायक छेदा सिंह चौहान की हत्या हुई, तो आरोप लगा था कि पूर्व राज्यमंत्री राजा विजय कुमार त्रिपाठी के संरक्षण में पल रहे लखनऊ के एक अपराधी गिरोह ने उनकी हत्या कर दी है। कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक चंदर सिंह पर ११ जनवरी, १९८३ को ब्रह्मदत्त शास्त्री की हत्या करने का आरोप लगा था, तो फैजाबाद के चर्चित नेता कृष्ण कुमार तिवारी को रामविलास की हत्या के आरोप में मिल्कीपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में उनकी भी हत्या हो गयी। जनता पार्टी के सवा दो वर्ष के शासनकाल में राजनेताओं पर चल रहे ७०० मुकदमों को सहर्ष वापस ले लिया गया था। फूलचंद यादव की हत्या करने के आरोप में लखनऊ के सुभाष भंडारी पर मुकदमा चला था, लेकिन बनारसी दास के मुख्यमंत्री बनने पर यह मुकदमा लोकहित में वापस ले लिया गया। सुभाष भंडारी हेमवती नंदन बहुगुणा की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के महासचिव बनाये गये थे।

संजय सिंह, रमाकांत यादव, मित्रसेन यादव, दूधनाथ यादव, फसीलुर्रहमान उर्फ मुन्नन खां और राजबहादुर विपक्षी दलों से संबद्ध वर्तमान विधानसभा के ऐसे सदस्य हैं, जिन पर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। रमाकांत यादव जौनपुर के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। १९८६ में फूलपुर थाने में उनके विरुद्ध हत्या और बलवा कराने का मुकदमा दर्ज हुआ। १९८७ में अपहरण की एक घटना में वे नामजद हुए थे। दूधनाथ यादव, जौनपुर के मड़ियाहूं क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी। फसीलुर्रहमान उर्फ मुन्नन खां गोण्डा जिले के कटराबाजार क्षेत्र से विधायक हैं। हत्या के प्रयास में उन्हें दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी। जौनपुर के विधायक राजबहादुर की गणना माफिया सरगनाओं में की जाती है। पुलिस के पास उनके आपराधिक रिकार्ड की मोटी फाइल है।

मिल्कीपुर क्षेत्र, जिला फैजाबाद के कम्युनिस्ट विधायक मित्रसेन यादव के आपराधिक कार्यों की एक लंबी कहानी है। १९६६ में वे मवई गांव में दो व्यक्तियों की हत्या के जुर्म में पकड़े गये। उच्चतम न्यायालय से भी वे दोषमुक्त न हो सके। अंत में राष्ट्रपति से उन्हें इस शर्त पर क्षमादान मिला कि सात वर्ष तक कोई अपराध नहीं करेंगे। चर्चा है कि क्षमादान दिलाने में केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव और प्रदेश के राज्यमंत्री राजमंगल पाण्डे ने उनकी बड़ी मदद की थी। १९७७ में वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से विधानसभा में पहुंचे। उसी वर्ष इनायतनगर थाने में उनके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। १९८२ में उनके खिलाफ डाका डालने का जुर्म दर्ज किया गया। कहते हैं, राष्ट्रपति से क्षमादान मिलने के समय उन्होंने नेकचलनी का जो हलफनामा भरा था, वह भी अब सरकारी अभिलेख से गायब है। एटा के पूर्व विधायक लूटरी सिंह जो अब कांग्रेस में आ गये हैं, के अतिरिक्त इसी जिले के गेंदालाल, महफूज अली, जसवीर सिंह आदि पर भी डाकुओं को संरक्षण देने के आरोप लगे थे।

मंत्रियों की छत्रछाया: वर्तमान मंत्रिपरिषद के चार मंत्रियों पर विधानसभा में आरोप लगाया गया है कि वे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। प्रदेश के नियोजन मंत्री रघुवीर सिंह यादव (मैनपुरी) पर डाकुओं को शरण देने के आरोप हैं, तो राजस्वमंत्री सीताराम निषाद पर १९७४ में फैजाबाद में हत्या के आरोप में मुकदमा चला था। उनके भाई जयराम निषाद और परिवार के नौ सदस्यों को १९७७ में हत्या के एक मामले में नामजद किया गया था। श्रमराज्यमंत्री ब्रजेन्द्रपाल सिंह यादव जब मुरादाबाद से लोकसभा के सदस्य थे, तब जिला अधिकारी ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया था। राज्यमंत्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा पर भी कई आपराधिक आरोप लगे हैं। कुशवाहा १९८४-८५ में नारायण दत्त तिवारी मंत्रिपरिषद में रहे, पर वीरबहादुर सिंह ने उन्हें अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया। नारायण दत्त तिवारी जब फिर मुख्यमंत्री बने, तब कुशवाहा फिर राज्यमंत्री बन गये।

सीताराम निषाद

वीरेंद्र प्रताप शाही

सितम्बर '१९८४ में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सदन में अपराधियों की राजनीति में घुसपैठ पर गहरी चिंता जतायी थी। अब वे पुनः मुख्यमंत्री हैं और उनकी चिंता भी बरकरार है। पर भाजपा के महामंत्री कलराज मिश्र का कहना है, "जब तिवारीजी खुद अपने ही मंत्रिमंडल में अपराध क्षेत्र से आनेवाले लोगों को शामिल किये हुए हैं, तब उनकी चिंता निरी राजनीतिक है, व्यावहारिक नहीं।" ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन को ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट करने के उपक्रम में लगा राजनेता और अपराधियों का यह गठजोड़ कब टूटेगा, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन लोग आशंका व्यक्त करने लगे हैं कि आगामी सर्दियों में आसन्न आम चुनाव लोकतांत्रिक नहीं रह पायेंगे तथा धनबल और भुजबल हर चुनाव क्षेत्र को हिंसक संघर्ष का मैदान बना देगा।

—लखनऊ ब्यूरो

कांग्रेस का कपाट कब खुलेगा?

हरिशंकर तिवारी

चिल्लूपार के विधायक और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बंदूक-पिस्तौल से वर्चस्व स्थापित करनेवाले गुट के नेता हरिशंकर तिवारी क्या कांग्रेस में आ रहे हैं? इधर कुछ समय से उन्हें जिस तरह 'ब्राह्मणों के नेता', 'पूर्वांचल के नेता' आदि नामों से उछाला जा रहा है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि तिवारी की अवाई की जमीन तैयार की जा रही है।

दरअसल वीरबहादुर सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो एक साथ वीरबहादुर सिंह, कमलापति त्रिपाठी, राजमंगल पांडेय आदि की कमी पूरी कर सके।

हरिशंकर तिवारी काफी अरसे से इस ताक में थे कि कोई खिड़की खुले और वे कांग्रेसी घर में घुस जायें। राज्य में मंत्री रह चुके प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बच्चा पाठक एक अरसे से प्रयत्नशील थे कि हरिशंकर तिवारी कांग्रेस में आ जायें। श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थीं और गोरखपुर गयी थीं, तब बच्चा पाठक ने कोशिश की थी कि किसी प्रकार हरिशंकर तिवारी को इंदिराजी के सामने लाया जाये। तिवारी को हवाई अड्डे ले जाया गया। पर वहां मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, जो हरिशंकर तिवारी के आपराधिक रिकार्ड से परिचित था, उन्हें प्रधानमंत्री के पास तक फटकने नहीं दिया।

हरिशंकर तिवारी तब सफल नहीं हुए, पर अपनी ब्राह्मणवादी छवि को बनाये रखने के लिए वे कमलापति त्रिपाठी का दामन थामें रहे। वीरबहादुर के उठ जाने और कांग्रेस को ब्राह्मण नेता की तलाश शुरू होने से हरिशंकर तिवारी को आशा बंधी है कि उनका रास्ता फिर खुलेगा और वे कांग्रेस में जा सकेंगे।

इसमें संदेह नहीं कि राजनीति और प्रचार माध्यमों में जो हरिशंकर के समर्थक हैं, वे इस विचार को हवा दे रहे हैं कि पूर्वांचल में अकेले तिवारी ही ऐसे नेता हैं जो कहीं से चुनाव लड़ और जीत सकते हैं। कमलापति त्रिपाठी के बाद हरिशंकर तिवारी अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें ब्राह्मण अपना नेता मानने को तैयार होंगे। वीरबहादुर सिंह के उठ जाने से ठाकुरों में नेतृत्व का जो संकट आया है, हरिशंकर तिवारी उसे भी काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में अपराधी गिरोह के एक अन्य नेता और विधायक वीरेंद्रप्रताप शाही ने, जो कुछ समय पूर्व तक तिवारी के जानी दुश्मन थे, अब 'पंडितजी' (हरिशंकर तिवारी) से समझौता कर लिया है।

बच्चा पाठक ने हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से मिलाया था। हरिशंकर तिवारी की कृष्णचंद्र पंत से भी घनिष्ठता है। खबर है कि वाराणसी में वीरबहादुर सिंह की अंत्येष्टि के समय पंत ने बलराम सिंह यादव से गंभीर मंत्रणा की थी और सुझाया था, "आप प्रधानमंत्री से आगे होकर अनुरोध करें कि हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में ले लिया जाये।" यह प्रचार जोरों पर है कि राजेंद्र कुमार धवन भी चाहते हैं कि हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में शामिल कर उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाये। माखनलाल फोतेदार को भी हरिशंकर तिवारी का पैरोकार बताया जाता है और कहा जाता है कि पंडित उमाशंकर दीक्षित, तिवारी पर पुत्रवत् स्नेह रखते हैं। उमाशंकर दीक्षित जब कर्नाटक के राज्यपाल थे, तब हरिशंकर तिवारी बंगलौर गये थे और वहां राजभवन में ही ठहरे थे।

कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित, हरिशंकर तिवारी के विरुद्ध हैं। बलराम सिंह यादव का मत भी यही है कि हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में लेने से पार्टी की छवि खराब होगी, क्योंकि हरिशंकर तिवारी अपराधकर्मियों के नेता हैं।

—रामपाल सिंह

जैट
और
बोस्की
सिर्फ़ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS.

Look Lovelier
this year
next year
every year
boski
BRA & PANTIES
VENUS HOSIERY
KANPUR·
PHONES : 65931 , 65921

Dealers enquiries are solicited in unrepresented areas.

असम

चावल घोटाले की कहानी, खुद पात्रों की जुबानी

इसी वर्ष फरवरी में असम सरकार ने विभिन्न फर्मों से १२ करोड़ रुपए का जो चावल खरीदा था, वह जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट का कहना है कि इस खरीदी में भारी अनियमितताएं बरती गयीं, लेकिन विक्षुब्ध विधायक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत के लिए यह घोटाला ऐसा फंदा बन गया है, जिससे उनका बच निकलना नामुमकिन है। 'माया' ने चावल खरीदी से जुड़े सरकारी अफसरों व विधायकों से इस मामले पर विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है, रिपोर्ट :

घोटाले में मेरा हाथ नहीं : प्रफुल्ल महंत

२० जून को असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत गुवाहाटी में नहीं थे। वे राष्ट्रीय मोरचे की बैठक में शरीक होने के लिए हैदराबाद गये हुए थे। उसी दिन असम के पूर्वमंत्री दिगेन बोरा से 'माया' की बात हो रही थी। दिगेन बोरा महंत की काबीना में उद्योगमंत्री हुआ करते थे। दिगेन ने 'माया' से कहा, "आज से आठ महीने पहले २३ अक्तूबर, १९८८ को जिस प्रफुल्ल महंत ने बस एक झटके में एक दर्जन मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से निकाल फेंका था, वे ही अब १२ करोड़ के चावल घोटाला कांड में उलझने के बाद 'स्टेटफेड' (असम कोआपरेटिव ऐंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लि०) के पूर्व प्रबंध निदेशक निरंजन घोष (जो इन दिनों मानव शक्ति विभाग के निदेशक हैं) से भी कैफियत पूछने की स्थिति में नहीं हैं। दरअसल, 'स्टेटफेड' द्वारा १२ करोड़ के चावल की खरीद में हुए घपलों के बारे में असम विधान सभा की जांच समिति की रिपोर्ट जब ६ जून को आयी और सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री भी इस संगीन घपले के घेरे में स्वाभाविक रूप से आ गये, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव एपी शरवान ने 'स्टेटफेड' के पूर्व प्रबंध-निदेशक निरंजन घोष को फौरन तलब किया। निरंजन ने विधान सभा की जांच समिति के समक्ष कहा था कि स्वयं मुख्यमंत्री ने बुलाकर उन्हें मौखिक आदेश दिया था और उसी आधार पर 'स्टेटफेड' को चावल आपूर्ति करने का अनुबंध उन व्यावसायिक कंपनियों तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किया गया, जिन्हें मुख्यमंत्री चाहते थे। मुख्य-सचिव ने निरंजन घोष से कहा कि अब उनकी भलाई इसी में है कि वे यह लिखकर दे दें कि 'स्टेटफेड' के पूर्व अध्यक्ष रूपम काकोटी के जरिये २८ अप्रैल, १९८९ को विधान सभा जांच समिति के सदस्य विधायक दिगेन बोरा ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था कि अगर जांच समिति के समक्ष वे मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे देते हैं, तो इस कार्य के लिए उन्हें चार-पांच लाख रुपए दिये जायेंगे।" दिगेन बोरा ने उत्तेजित होकर 'माया' से आगे बताया, "मुख्यमंत्री ने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की, पर शुक्र है, निरंजन घोष को समय रहते अकल आ गयी और उन्होंने दुबारा पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मेरे विरुद्ध मुख्य सचिव ने ही उनसे लिखाया था।" दिगेन बोरा अपनी बात समाप्त करने ही वाले थे कि उसी समय 'स्टेटफेड' के पूर्व विवादास्पद अध्यक्ष रूपम काकोटी उनके यहां आ गये।

रूपम काकोटी ने 'माया' से कहा, "दरअसल, शुरू से अब तक हमारे मुख्यमंत्री की यही कार्यशैली रही है कि वे दूसरों को बलि का बकरा बनाकर अपना काम निकालते रहे हैं। 'स्टेटफेड' में बतौर अध्यक्ष मैंने चावल की खरीद में जो कुछ किया, वह मुख्यमंत्री के आदेश से ही। पर जब फंदे में फंसने की बारी आयी, तो मेरा गला फंदे में डाल, वे खिसकने लगे। पूर्व स्वास्थ्यमंत्री चंद्रमोहन पटवारी के साथ भी महंत ने यही सलूक किया था। पटवारी के माध्यम से वे 'फंड कलेक्शन' करवाते थे और जब यह बात खुलने लगी, तो अचानक पटवारी को भ्रष्ट बता कर मंत्रिमंडल से निकाल दिया। विधानसभा में 'स्टेटफेड' के जरिये चावल खरीद के मामले पर जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट पेश होने के ठीक बारह दिन पहले, यानी २३ मई को मुझे 'स्टेटफेड' के चेयरमैन पद से स्थानांतरित कर 'असम खनिज विकास निगम' के चेयरमैन पद पर भेजने का आदेश मुख्यमंत्री ने सोची-समझी रणनीति के तहत इसलिए दिया कि अगर मैं 'स्टेटफेड' के चेयरमैन पद पर रहा, तो कहीं मजबूर होकर मैं उनके खिलाफ मुंह न खोल दूं। 'स्टेटफेड' से हटाकर महंत ने मुझे खनिज विकास निगम में भी पद सिर्फ इसलिए दिया कि मैं क्षुब्ध होकर असलियत न खोलने लगूं। अभी तो चावल खरीद के घपले पर विधान सभा समिति की अंतरिम रिपोर्ट ही आयी है। पूरी रिपोर्ट अगस्त, १९८९ तक आयेगी। महंत मुझे इसलिए अगस्त तक पद देकर चुप रखना चाहते थे। अगर यह पेंच न रहता, तो महंत सीधे मुझे चोर करार दे कर अब तक निकाल चुके होते। इसलिए मैं चेत गया। मुझे लगा कि महंत मेरा शिकार करने की कोशिश में हैं। इसलिए अब तक मैंने खनिज विकास निगम में अध्यक्ष का पद-भार भी नहीं संभाला है। मैंने विगत ९ जून को असम गण परिषद् के दो महासचिवों गृहमंत्री भृगु फूकन तथा लोक निर्माण मंत्री अतुल बोरा को पत्र लिखकर तत्काल पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाने और यह फैसला करने की मांग की कि चावल की खरीद में दोषी कौन है ? मुख्यमंत्री महंत या मैं ? मैंने अपने इस पत्र में उन सभी प्रसंगों का उल्लेख किया है कि कैसे एक दिन पार्टी के दफ्तर में मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि 'स्टेटफेड' को चावल आपूर्ति का आदेश मैं अमुक-अमुक पार्टी को ही दूं, क्योंकि इससे २५ लाख कमीशन मिलनेवाला है। जिस समय मुख्यमंत्री मुझसे यह कह रहे थे, उस समय वहां लोकनिर्माण मंत्री तथा पार्टी महासचिव अतुल बोरा भी बैठे हुए थे। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि चावल आपूर्ति का ठेका उन व्यावसायिक कंपनियों को देने

के बजाय अगर बेरोजगार युवकों को दिया जाये, तो इससे अपनी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पर महंत ने अडिग होकर कहा कि २५-३० लाख का घाटा वे नही सह सकते। वे उन व्यावसायिक कंपनियों तथा आपूर्तिकर्ताओं से सारी बात कर चुके हैं।'' क्या सचमुच मुख्यमंत्री महंत ने रूपम काकोटी से चावल खरीद के मामले में २५ लाख रुपए कमीशन की बात की थी?

खर्च का सवाल: असम गण परिषद् के महासचिव तथा लोक निर्माण मंत्री अतुल बोरा 'माया' से कहते हैं, ''जिस दिन की बात रूपम काकोटी कह रहे हैं, उस दिन मैं पार्टी के दफ्तर में जरूर था। पार्टी का खर्च कैसे चलेगा, इसको लेकर कुछ चर्चा अवश्य चल रही थी। पर मुख्यमंत्री ने एक बार भी रूपम से पैसे की बात नही कही। हां, मैंने रूपम से और वहां मौजूद पार्टी के सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि पार्टी का खर्च चलना भी जरूरी है, पर ऐसा कोई काम न हो, जिससे पार्टी की छवि पर चोट पहुंचे।'' पर संगीन चावल घोटाला जांच संबंधी असम विधान सभा की समिति के अध्यक्ष तथा नलबाड़ी क्षेत्र से असम गण परिषद् के विधायक नागेन शर्मा 'माया' से कहते हैं, ''असम की आम जनता के बीच पार्टी की छवि को इससे जबर्दस्त धक्का तो लग ही गया। यह मामला इस प्रदेश के गरीब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ है। लोग इस बात को आसानी से नहीं भूल सकेंगे।''

आज से आठ माह पूर्व नागेन शर्मा महंत की काबीना में पशुपालन तथा मत्स्य-विभाग के काबीना मंत्री थे। १९८८ के अक्तूबर माह में जब महंत ने एक दर्जन मंत्रियों को अपनी काबीना से रुखसत किया था, तो उनमें एक नागेन शर्मा भी थे और इसलिए जब चावल कांड संबंधी अंतरिम रिपोर्ट में सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री महंत भी निशाने पर चले गये, तो महंत-समर्थकों ने कहना शुरू किया कि विधान सभा की उक्त समिति के अध्यक्ष, क्योंकि नागेन शर्मा थे तथा सदस्यों में महंत-मंत्रिमंडल से बर्खास्त दिगेन बोरा थे, इसलिए महंत के इन विक्षुब्धों ने अंतरिम रिपोर्ट में महंत पर हमला कर दिया। इस पूरे विवाद के संबंध में नागेन शर्मा ने 'माया' को बताया, ''सचाई से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस किस्म की सुनियोजित चर्चा जोर-शोर से की गयी। इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए १६ जून को हमने प्रेस कांफ्रेंस भी की और पत्रकारों को बताया कि चावल घोटाला संबंधी विधान सभा समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक-एक पंक्ति साक्ष्य पर आधारित है। मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि तमाम भेद-भाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से पूरे मामले की जांच की गयी। फिर यह तो अंतरिम रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट तो अगस्त तक आयेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री ने जब पाया कि विधान सभा समिति इस मामले में सचाई की रग पकड़ चुकी है और पूरी रिपोर्ट जब आयेगी, तो पता नहीं क्या होगा, बस इसी आशंका के तहत उन्होंने समिति को ही विवादास्पद बनाने का अभियान छेड़ दिया। इस मामले में कई दिग्गज फंसनेवाले हैं। मजे की बात यह है कि जब इसी वर्ष १५ मई को विधानसभा में इस घपले की जांच के लिए विधान सभाध्यक्ष ने समिति का गठन किया और मुझे अध्यक्ष बनाया, तब तो मुख्यमंत्री या उनके कथित शुभचिंतकों ने कोई आपत्ति नही की थी। वे उसी समय कह सकते थे कि इस समिति में उनके विरोधी अध्यक्ष व सदस्य बनाये गये हैं, इसलिए उन्हें संदेह है। पर अब जबकि अंतरिम रिपोर्ट आ गयी है और पूरी रिपोर्ट आनेवाली है, तो बावेला मच रहा है। वह चावल जिसे करोड़ों में खरीदा गया, वह आदमी के खाने योग्य था ही नही और यह खरीद मुख्यमंत्री के लिखित तथा मौखिक आदेश पर हुई। असम की जनता को हम क्या मुंह दिखायेंगे? क्या यह बात लोग नहीं पूछेंगे कि असम गण परिषद् की सरकार हमलोगों को जानवर समझती है और इसीलिए मानव व्यवहार के लिए सर्वथा अनुपयुक्त चावल लोगों को इस सरकार ने खिलवाया। अगर मुख्यमंत्री यह उम्मीद करते थे कि उनकी पार्टी के विधायक होने के नाते हम आरोपों के बवंडर से उन्हें उबार लेंगे, तो यह संभव नहीं था, क्योंकि समिति में सात सदस्य हैं, जिनमें तीन सदस्य हेमेन दास (सीपीएम के विधायक), हिरण्य बोरा (इंका विधायक) तथा इमानुल इस्लाम (निर्दलीय विधायक) विपक्षी दलों के थे। ये तीनों अगर देखते कि हम मुख्यमंत्री को बचाने की फिराक में सही तथ्यों को दबा रहे हैं, तो जबर्दस्त हंगामा हो जाता और विधान सभा समिति की मर्यादा का हनन होता। समिति में असम गण परिषद् के विधायक पूर्वमंत्री रमेंद्र नारायण कालिता भी एक सदस्य थे। अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होने तक वे समिति की प्रत्येक कार्यवाही में शामिल रहे, पर अचानक ८ जून को उन्होंने समिति की सदस्यता से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि अंतरिम रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका हस्ताक्षर नहीं है और रिपोर्ट से वे सहमत नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रमेंद्र नारायण कालिता ने ऐसा मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के लिए किया। २३ जून को जब मुख्यमंत्री ने कालिता को मंत्री बनाकर पुरस्कृत किया, तो यह बात साबित हो गयी।''

पैसों की बात नहीं हुई: अतुल बोरा

मुख्यमंत्री विरोध: पुलकेश बरुआ

विक्षुब्धों को चेतावनी: सचमुच २३ अक्तूबर, १९८८ और २३ जून, १९८९ में कहीं कोई फर्क नहीं था। २३ अक्तूबर, १९८८ को जहां महंत ने अपने मंत्रिमंडल से एक दर्जन मंत्रियों को बर्खास्त कर बता दिया कि विक्षुब्धों को कुचलने में वे कतई कमजोर नहीं हैं, वहीं २३ जून, १९८९ को अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ दो मंत्रियो को शामिल कर महंत ने ऐलान कर दिया कि उनके मंत्रिमंडल में उन्हीं विक्षुब्धों को फिर जगह मिल सकती है जो उनके शरणागत बनकर आयेंगे। २३ जून को महंत ने अपने मंत्रिमंडल के संक्षिप्त विस्तार से वाकई विक्षुब्धों को गहरी चोट दी। महंत मंत्रिमंडल में शामिल इन दो मंत्रियों में एक भरतचंद्र नरह थे, जिन्हें विक्षुब्ध होने के कारण महंत ने काफी पहले मंत्रिमंडल से निकाला था। भरत उस समय राज्यमंत्री हुआ करते थे। पर इस बार भरत को महंत ने काबीना स्तर का मंत्री बना दिया। पश्चिमी गुवाहाटी क्षेत्र से असम गण परिषद् विधायक रमेंद्र नारायण कालिता को आठ माह पूर्व उद्योग राज्यमंत्री पद से विक्षुब्ध गतिविधियों के कारण महंत ने फुर्सत दे दी थी। पर जब हाल में विधान सभा समिति की सदस्यता से मुख्यमंत्री की तरफदारी में रमेंद्र नारायण कालिता ने त्यागपत्र देकर अपने विक्षोभ का प्रायश्चित किया, तो महंत ने फिर उन्हें उनकी राज्य मंत्रीवाली कुरसी वापस कर दी। हां, 'स्टेटफेड' के पूर्व प्रबंध-निदेशक निरंजन घोष को भी महंत ने चावल खरीद के घोटाले के आरोप में मंत्रिमंडल के इस लघु विस्तार के तत्काल बाद ही निलंबित कर दिया। महंत समर्थक 'माया' से कहते हैं कि महंत ने दोबारा उन तमाम विक्षुब्धों को हिदायत दे दी है कि ललकारनेवालों को वे किसी भी हालत में लाभ नहीं देनेवाले। पर विक्षुब्ध आश्वस्त हैं कि १२ करोड़ का चावल खरीदी घोटाला ऐसा फंदा है, जिससे महंत बच ही नहीं सकते।

अंतरिम रिपोर्ट का खुलासा: महंत के गले का फंदा बन चुकी समिति की अंतरिम रिपोर्ट इस प्रकार है, ''२८ अप्रैल, १९८९ को विधान सभा माननीय सदस्यों सर्वश्री कमला कालिता, नागेन शर्मा, रमेंद्र नारायण कालिता और दिगेन बोरा ने शून्यकाल के दौरान १२ करोड़ के चावल खरीदी घोटाले से संबंधित एक अत्यंत गंभीर मामला उठाया था। कमला कालिता ने कहा था कि स्टेटफेड ने असम में आमलोगों के बीच जिस चावल की आपूर्ति की, वह इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं था। कमला कालिता का आरोप था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 'स्टेटफेड' ने ५८ व्यावसायिक फर्मों तथा आपूर्तिकर्ताओं को चावल आपूर्ति का आदेश दिया और गलत ढंग से करोड़ों की राशि का भुगतान कर दिया। आपूर्ति आदेश से लगभग ५००० क्विंटल कम चावल की आपूर्ति उन व्यावसायिक फर्मों ने की, पर उसकी भी कीमत १३ लाख रुपए 'स्टेटफेड' द्वारा रहस्यमय ढंग से अदा कर दी गयी। बगैर क्वालिटी कंट्रोल विभाग से उन चावलों की जांच कराये, 'स्टेटफेड' ने व्यावसायिक फर्मों को आंख मूंदकर ८५ प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान भी कर दिया था।'' सदन में कमला

कालिता ने इस गभीर मामले की पूरी जांच कराने की मांग की। उस दिन सदन के सभी सदस्यों ने एक सुर से विधान सभाध्यक्ष से अनुरोध किया कि विधान सभा की एक जांच समिति गठित कर दी जाये। लिहाजा, १५ मई, १९८९ को विधान सभाध्यक्ष पुलकेश बरुआ ने विधान सभा की एक समिति गठित कर दी। सात सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष नागेन शर्मा बनाये गये। असम विधान सभा के सचिव एसएन देका ने समिति के गठन की अधिसूचना में यह उल्लेख किया कि समिति किन-किन बिंदुओं पर जांच करेगी। मसलन, यह कि क्या 'स्टेटफेड' द्वारा चावल आपूर्ति के लिए विधिवत टेण्डर आमंत्रित किये गये? 'स्टेटफेड' द्वारा जिन फर्मों को आपूर्ति का आदेश दिया गया, क्या वह उचित था? भुगतान करने के पहले क्या चावल की कोटि की जांच की गयी? क्या आदेश से कम चावल की आपूर्ति हुई? इस घपले में कौन लोग संलग्न हैं तथा इस घपले की जानकारी के बाद 'स्टेटफेड' ने प्रतिकारस्वरूप क्या कोई कदम उठाया, जिससे संस्था के हितों की रक्षा होती? समिति की अधिसूचना में कहा गया था कि तीन माह के भीतर पूरी जांच-रिपोर्ट तथा बीस दिनों के अंदर अंतरिम रिपोर्ट समिति अवश्य पेश कर दे। तदनुसार समिति ने ६ जून को अंतरिम रिपोर्ट सदन में पेश कर दी।

२३ मई, १९८९ को समिति ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव से पूछा कि किस वर्ष से 'स्टेटफेड' द्वारा चावल की खरीद का कारोबार चल रहा है तथा खाद्य आपूर्ति विभाग ने 'स्टेटफेड' को कब चावल खरीदने का आदेश दिया था? सचिव ने समिति को बताया कि २ नवंबर, १९८८ को पहली बार १.०८ लाख टन चावल की खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्टेटफेड को आदेश दिया था। सचिव ने समिति को यह स्पष्ट किया कि इस पहले आदेश के पीछे भी 'स्टेटफेड' का ही प्रस्ताव था। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने समिति को बताया, "२३ मई, १९८९ तक चावल की कोटि की जांच के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहकारिता विभाग द्वारा दिये गये उत्तर पर जब समिति की दृष्टि गयी, तो पाया गया कि २५ अक्तूबर, १९८८ को 'स्टेटफेड' द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि खरीफ के मौसम में १९८८-८९ के वास्ते अन्न प्राप्त करने हेतु उधार की सुविधा सरकार दे। सरकार से स्वीकृति पाकर 'स्टेटफेड' की कार्यकारिणी ने १७ दिसंबर, १९८८ को १.०८ लाख टन लेवी मुक्त चावल पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के खुले बाजार से १९८९ के फरवरी माह के भीतर अत्यंत कम कीमत पर खरीदने का फैसला किया। इसके बाद ही 'स्टेटफेड' ने ५८ व्यावसायिक फर्मों और आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची तैयार कर ली। प्रति क्विंटल चावल 'स्टेटफेड' के गुवाहाटी स्थित गोदाम तक पहुंचाने की दर ४०८ रुपए निर्धारित कर दी गयी। लेकिन २५ फरवरी, १९८९ को अचानक 'स्टेटफेड' की कार्यकारिणी की बैठक में स्टेटफेड के तत्कालीन अध्यक्ष रूपम काकोटी तथा तत्कालीन प्रबंध निदेशक निरंजन घोष ने जानकारी दी कि चावल की आपूर्ति करने के लिए जिन व्यावसायिक फर्मों का चयन किया गया था, उन सबों ने अब तक चावल की आपूर्ति नही की है और साथ ही खरीद की दर में वृद्धि का अनुरोध किया है। लिहाजा, उसी दिन की बैठक में चावल की कीमत में ४०८ रुपए प्रति क्विंटल से ४२१ रुपए की वृद्धि कर दी गयी, साथ ही यह भी तय किया गया कि ८५ प्रतिशत राशि का भुगतान चावल आपूर्ति करनेवाली फर्मों को रेलवे का 'आरआर' (बिल्टी) प्रस्तुत करने पर ही कर दिया जायेगा।

"समिति ने जांच के दौरान सभी कागजात को छान मारा पर कहीं से यह संदर्भ नहीं मिला कि आखिर किस आधार पर १.०८ लाख टन चावल, जिसकी कीमत १२ करोड़ से अधिक ही थी की आपूर्ति करने के लिए व्यावसायिक फर्मों का चयन किया गया। जब समिति ने जानना चाहा कि क्या इसके लिए कोई टेण्डर या किसी तरह की सूचना जारी की गयी, तो सहकारिता विभाग के आयुक्त व सचिव ने कहा कि कोई टेण्डर या सूचना जारी नहीं की गयी थी। समिति ने उन ५८ व्यावसायिक फर्मों के मूल आवेदन पत्रों को भी बारीकी से जांचा।

नीयत पर संदेह:
दिगेन बोरा

जांच तथ्यपरक है:
नागेन शर्मा

आवेदन पत्रों की जांच के दौरान समिति ने पाया कि कई फर्मों के आवेदन जिसे चावल आपूर्ति का आदेश दिया गया था, पर सहकारिता मंत्री (स्वयं मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत इस विभाग के प्रभारी मंत्री रहे हैं) की स्पष्ट अनुशंसा है। समिति का मानना था कि व्यावसायिक फर्मों के चयन का आधार मुख्यत: सहकारिता मंत्री की लिखित व मौखिक अनुशंसा ही थी। समिति ने 'स्टेटफेड' के तत्कालीन प्रबध निदेशक निरंजन घोष से जानना चाहा कि सूरज हजारिका, हेमंत दास, दिलीप गोस्वामी तथा सुबन श्री इंटरप्राइजेज के एनआर बरुआ को किस आधार पर चावल-आपूर्ति का आदेश दिया गया, तो निरंजन घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए मौखिक आदेश दिया था।"

अंतरिम रिपोर्ट के पृष्ठ १९ पर समिति ने टिप्पणी करते हुए लिखा है, "चावल आपूर्ति की अनियमितता में प्राप्त साक्ष्यों के मुताबिक यही नतीजा निकलता है कि सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री की भूमिका निस्संदेह अनुचित थी।" समिति ने आगे लिखा है, "गुवाहाटी के चांदमारी में स्थित मेसर्स इम्पीरियल ट्रेडिंग जो उन ५८ व्यावसायिक फर्मों में से एक हैं, जिसे चावल की आपूर्ति करनी थी, की भूमिका आपत्तिजनक है। इसके मालिक प्रदीप साईकिया ने 'स्टेटफेड' के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा कि वह चावल आपूर्ति करने की अपनी जिम्मेवारी गुवाहाटी के पलटन बाजार में मुहम्मदशाह रोड स्थित 'मेसर्स सुरेश कुमार ऐंड कंपनी' को देती है। प्रदीप साईकिया ने अपने इस पत्र के साथ सुरेश कुमार ऐंड कंपनी को अपने द्वारा दी गयी पावर आफ एटार्नी की प्रति भी संलग्न कर दी थी। पर मामला यहीं तक नहीं रहा। 'सुरेश कुमार ऐंड कंपनी' के मालिक सुरेश कुमार गारोदिया ने भी पंजाब के कपूरथला की 'मेसर्स बब्बूराम जगदीश कुमार ऐंड कंपनी' से ११ मार्च, १९८९ को दिल्ली में अनुबंध किया कि सुरेश कुमार ऐंड कंपनी की जगह अब मेसर्स बब्बूराम जगदीश कुमार ऐंड कंपनी ही 'स्टेटफेड' को चावल की आपूर्ति कर देगी।" समिति ने इस तरह के घालमेल को अत्यंत संदेहास्पद और अवैध माना है। समिति ने लिखा है कि २१ मार्च, १९८९ को 'स्टेटफेड' के अध्यक्ष रूपम काकोटी जो उन दिनो दिल्ली गये हुए थे को दिल्ली में 'सुरेश कुमार ऐंड कंपनी' की ओर से एक पत्र मिला। पत्र में अनुरोध किया गया था कि मेसर्स बब्बूराम जगदीश कुमार ऐंड कंपनी को चावल आपूर्ति करने के लिए ८५ प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान कर दिया जाये। 'स्टेटफेड' के अध्यक्ष ने अपने प्रबंध निदेशक से मशविरा किया और फिर उतनी राशि का भुगतान मेसर्स बब्बूराम जगदीश कुमार ऐंड कंपनी को कर दिया गया।" समिति ने टिप्पणी की है कि बगैर चावल की जांच पड़ताल किये कि चावल की कोटि क्या है और क्या आदेश के अनुरूप चावल की आपूर्ति हुई है? जिस तरह से उक्त कंपनी को भुगतान किया गया, वह अत्यंत आपत्तिजनक है। समिति ने जांच के क्रम में पाया कि इसी तरह दिल्ली की 'मेसर्स इस्के इंटरप्राइजेज' ने भी धंधा किया। चावल आपूर्ति के लिए जिन ५८ फर्मों को आदेश हुआ था, उनमें से ग्यारह फर्मों ने अपना पावर आफ एटार्नी दिल्ली की इस कंपनी के नाम कर दिया। समिति ने इतनी संख्या मे पावर आफ एटार्नी की वैधता के बारे में जब कानूनी राय ली, तो अधिवक्ता सीके शर्मा बरुआ ने कहा कि यह गैरकानूनी है।"

महंत की प्रतिक्रिया: बहरहाल ३१ मई १९८९ तक सभी विवादास्पद फर्मों को कुल मिलाकर ११, १७, ६१, ९७३ रुपए का भुगतान हो चुका है। मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत ने चावल कांड के काफी गहराने के पश्चात कहा कि इस मामले में उन्हें सुनियोजित रूप से घसीटा गया है। महंत ने इस मामले की जांच की जिम्मेवारी असम के सीआईडी विभाग को देने की घोषणा तो की ही, साथ ही सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी से भी अपने को मुक्त कर इस विभाग को मंत्री पद्मेश्वर दोले के हवाले कर दिया। पर क्या महंत यह सब करके चैन पा लेंगे?

छाया : दीपक कुमार

—विकास कुमार झा

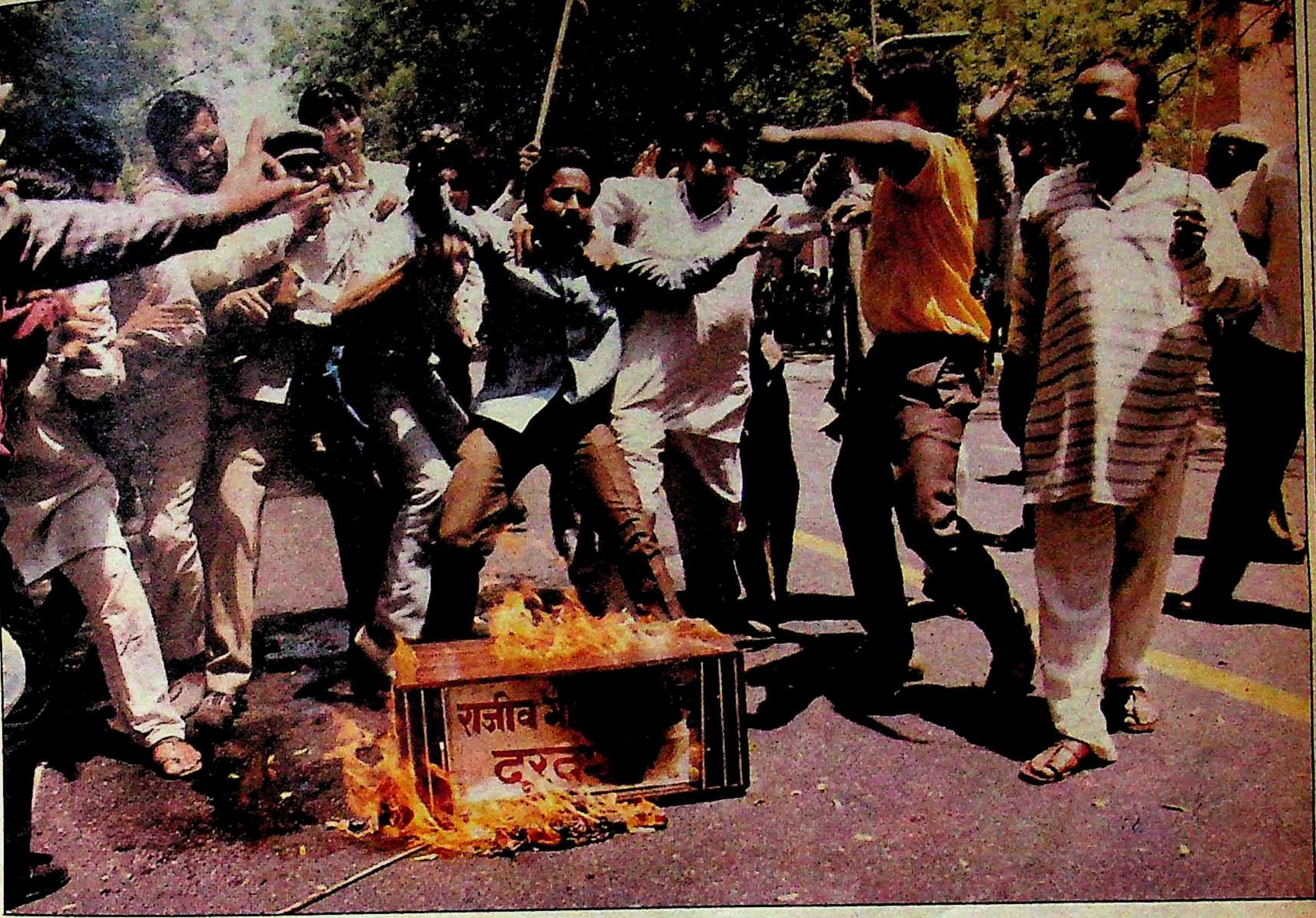

दूरदर्शन का कांग्रेसीकरण

दूरदर्शन और रेडियो के खिलाफ विपक्षी दलों ने ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया, जैसा इस बार २५-२६ जून को किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी सूचना माध्यमों-खासकर दूरदर्शन को सत्तारूढ़ दल ने अपने प्रचार और विपक्ष के दुष्प्रचार का साधन बना लिया है। दूरदर्शन के सर्वव्यापी प्रभाव और चुनाव की सन्निकटता को देखते हुए विपक्ष और भी ज्यादा आतंकित लगता है। दूरदर्शन ने हाल में ऐसा कौन सा रवैया अपनाया है, जिसके कारण यह राष्ट्रव्यापी विवाद का विषय बन गया है? दूरदर्शन की न्यायोचित नीति क्या होनी चाहिए और इस नीति को कब-कब क्यों बदला गया? ऐसे कौन से ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूरदर्शन का कांग्रेसीकरण हो गया है?

३१ अक्तूबर, १९८४। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान जब कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राजीव गांधी को अचानक वायरलैस द्वारा अपनी मां प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर कातिलाना हमले की सूचना मिली, तो समाचार की पुष्टि और विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर तुरंत खोल लिया। विडंबना ही है कि देश की राजधानी में घटी इस दुखद घटना की प्रामाणिक जानकारी के लिए उन्होंने आकाशवाणी की जगह बीबीसी लगाना बेहतर समझा। राष्ट्रीय सूचना-प्रसारण-माध्यमों की विश्वसनीयता पर लगे प्रश्न-चिह्न का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ? गांधी की प्रतिक्रिया अनुचित अथवा असंगत नहीं थी, क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही देर शाम तक सत्य को प्रकाशित करने में हिचकिचाते रहे थे।

इसके बाद श्रीमती गांधी के शव और उसके आसपास की घटनाओं का तीन दिन तक जिस तरह प्रदर्शन-प्रसारण हुआ, उसने इन आरोपों को जन्म दिया कि कांग्रेस-इ ने अपने प्रति सहानुभूति की लहर उत्पन्न करने के लिए दूरदर्शन-आकाशवाणी का दुरुपयोग किया। १९८४ के घृणित दंगों के भड़कने का एक कारण यह दुरुपयोग भी माना गया।

तब से शुरू हुए आरोपों में पांच वर्ष बाद और तेजी आयी है। विपक्ष सरकारी मीडिया पर लगातार पक्षपात करने और सरकारी भोंपू बन जाने का आरोप लगा रहा है। विपक्षी असंतोष, आक्रोश की चरम परिणति गत २५-२६ जून को आपातकाल की चौदहवीं वर्षगांठ के अवसर पर 'सरकारी मीडिया' के दुरुपयोग के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी धरने, प्रदर्शन और लगभग एक लाख लोगों की गिरफ्तारियों के रूप में हुई। कई स्थानों पर हुए लाठीचार्ज में लगभग पांच दर्जन प्रदर्शनकारी घायल हुए। विपक्ष का दावा है कि भरपूर चुनावी लाभ उठाने के लिए राजीव सरकार और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रभावशाली माध्यम को न सिर्फ बंधक बना लिया है, बल्कि अपनी छवि निखारने और विपक्ष की छवि नष्ट करने के लिए उसका तेजी से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि ज्यों-ज्यों प्रचार-प्रसार के दृश्य-श्रव्य माध्यमों का विस्तार हुआ है, त्यों-त्यों उसका महत्व भी बढ़ा है और सरकार की पकड़ भी बढ़ी है (देखें-बाक्स)। आज स्थिति यह है कि जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह दूरदर्शन को 'दुष्ट दर्शन' और आकाशवाणी को 'झूठ वाणी' की संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं, "मीडिया जनता के पैसे से चल रहा है। यह कोई कांग्रेस-इ के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी का खजाना नहीं है, जिससे 'शो' चलाया जा रहा है। देश का इलेक्ट्रानिक मीडिया इंका के लिए पार्टी प्रचार का जरिया बनकर रह गया है।"

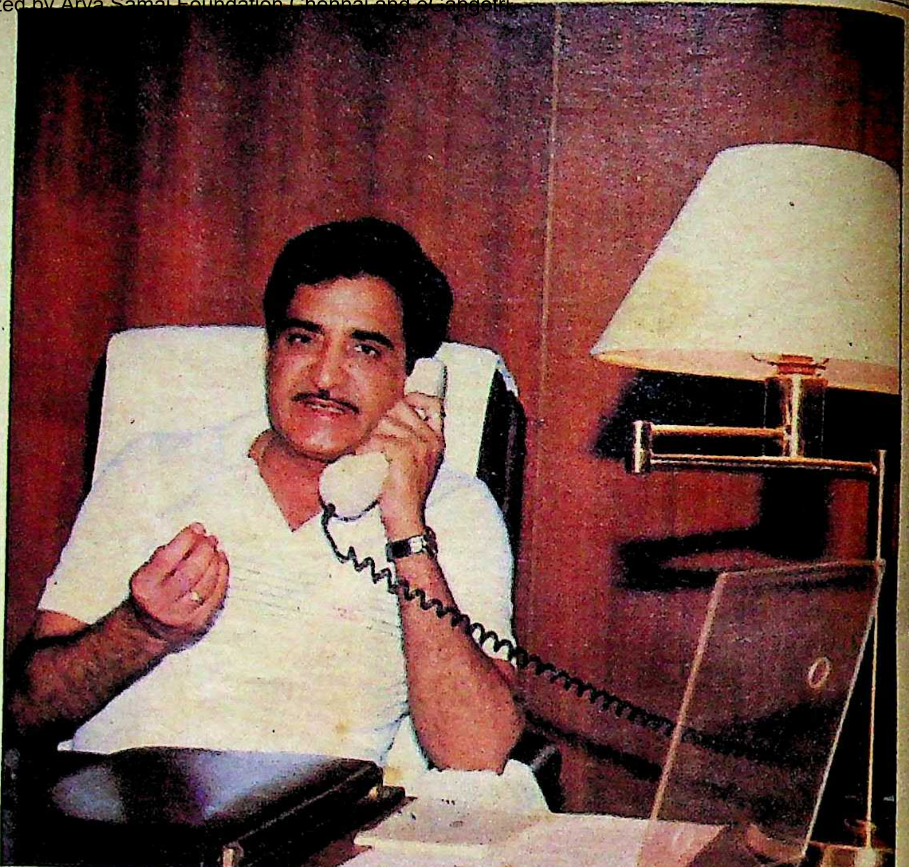

जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में स्वायत्तता क्यों नहीं दी ?: केके तिवारी

छाया: सुनील सक्सेना

सराहनीय शुरुआत : विडंबना है कि राजीव गांधी ने सत्तारूढ़ होने के बाद बंबई में कांग्रेस शताब्दी समारोह के अपने ऐतिहासिक भाषण में जिस प्रकार सत्ता के दलालों से कांग्रेस को मुक्त करने का आह्वान किया था, उसी जोशखरोश से उन्होंने दूरदर्शन-रेडियो को नौकरशाही की जकड़बंदी से मुक्त कर विश्वसनीय बनाने का भी आश्वासन दिया था। नतीजतन, दूरदर्शन में 'जनवाणी', 'सच की परछाइयां', 'न्यूजलाइन' 'रजनी', 'नुक्कड़' जैसे बहुचर्चित निष्पक्ष कार्यक्रमों और यथार्थपरक सीरियलों का प्रवेश पहली बार छोटे परदे पर हुआ, जिनको भरपूर सराहा गया।

यही नहीं, १९८६ में प्रधानमंत्री ने स्वयं एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा कि दूरदर्शन उन्हें आवश्यकता से अधिक 'कवरेज' दे रहा है। उन्होंने घोषित किया कि इससे लाभ की अपेक्षा हानि होगी। प्रधानमंत्री की इस प्रकार की बयानबाजी मात्र छलावा थी, ऐसा भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी का दावा है। 'माया' से एक निजी अनुभव का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के अति प्रचार के मुद्दे पर 'न्यूजलाइन' के एक कार्यक्रम के लिए विनोद दुआ ने अमिता मलिक, वीएन गाडगिल और उनसे बातचीत कर फिल्म बनायी थी। किंतु उसे आज तक दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया है। कारण स्पष्टतया यही है कि इस

छाया: मनमोहन शर्मा

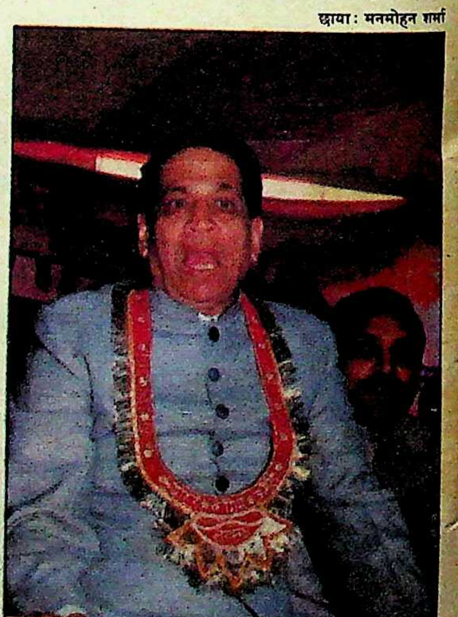

विपक्ष का राजीव हटाओ कार्यक्रम प्रसारित क्यों करें ? : साठे

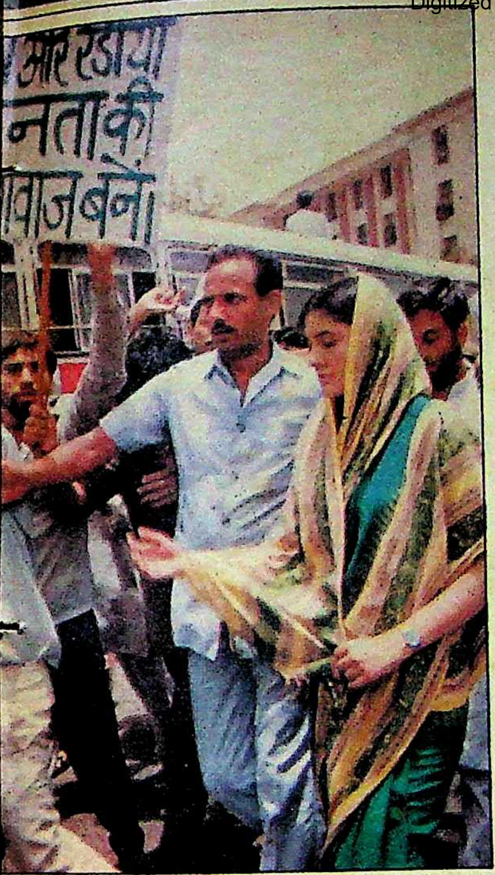

दूरदर्शन के रवैये के विरुद्ध: मेनका गिरफ्तारी देते हुए

नील सक्सेना

नमोहन शर्मा

मुद्दे पर हमने आलोचनात्मक रुख अपनाया था।

आलोचना पर प्रतिबंध भले ही रहा हो, किंतु प्रधानमंत्री के अति प्रचार-प्रसार पर लगाम लगाने की नीति एक सुविचारित रणनीति के तहत थी, ऐसा राजीव गांधी के तत्कालीन प्रमुख सलाहकार, सिपहसालार अरुण नेहरू का कहना है। उनके अनुसार ऐसा निर्णय इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए लिया गया था कि प्रधानमंत्री की कभी-कभार की झलकियों से दर्शकों में उनके प्रति उत्सुकता और आकर्षण रहेगा। प्रारंभिक दिनों में यह नीति रंग लायी। प्रधानमंत्री की छवि एक युवा, प्रगतिशील और उदार नेता के रूप में दर्शकों के मन में घर कर गयी। प्रधानमंत्री ही नहीं, दूरदर्शन की लोकप्रियता में भी चार चांद लगे। राजीव गांधी के शासन काल में इलेक्ट्रानिक मीडिया का स्वर्णकाल भास्कर घोष, गोपीकृष्ण अरोड़ा और सुमन दुबे की त्रिमूर्ति के कार्यकाल के दौरान रहा। स्मरणीय है कि बोफोर्स जैसे सरकार को कटघरे में खड़ा करनेवाले विस्फोटक मुद्दे पर भी एक लगभग खुली बहस दूरदर्शन द्वारा इसी काल में दिखायी गयी।

अशुभ संकेत: दूरदर्शन संबंधी नीति में परिवर्तन का प्रथम संकेत महानिदेशक भास्कर घोष की बर्खास्तगी से प्राप्त हुआ। इसका फौरी कारण 'नेशनल हेराल्ड' के रजत जयंती समारोह के उस समाचार-दृश्य को दिखाया जाना रहा, जिसमें मानहानि विधेयक के खिलाफ नारों की उभरती आवाज में राजीव गांधी की आवाज (भाषण) दब गयी थी। किंतु सामान्य कारण यह था कि सरकार नीति-परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थी और 'ग्लासनास्त' (खुलेपन) का श्रीगणेश करने और विश्वसनीयता के लिए व्यावसायिक महारत को महत्व देनेवाले घोष की मौजूदगी इसमें कांटा सिद्ध होती। सरकारी चाल तब और उजागर हुई, जब नये महानिदेशक के रूप में विभाग के पुराने नौकरशाह और हिदायत से सूत भर इधर-उधर न हिलनेवाले शिव शर्मा की तैनाती हुई। अंतिम संकेत कर्नाटक में बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी के बाद रातोरात बड़बोले और विपक्ष के पीछे डंडा लेकर घूमनेवाले केके तिवारी की सूचना प्रसारण राज्यमंत्री पद पर नियुक्ति से मिला।

तिवारी का प्रवेश: तिवारी की नाटकीय तैनाती को लेकर अटकलों-अफवाहों का बाजार गर्म रहा। विशेषकर, इसलिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में दो मंत्री-हरकिशनलाल भगत और कृष्ण कुमार पहले से ही मौजूद थे। यद्यपि आम धारणा यही रही कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू होने के समाचार का दूरदर्शन पर अप्रभावी प्रसारण तेजतर्रार तिवारी की नियुक्ति का प्रमुख कारण था, किंतु जानकार सूत्रों का दावा है कि सन्निकट चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही इस मौके का लाभ उठाया गया था।

रणनीति त्रिमुखी थी। एक, तिवारी को हरावल दस्ता बना मैदाने-जंग में उतार विपक्ष की मिट्टीपलीत करना। दूसरा, तिवारी की आड़ में परदे के पीछे से तीरंदाजी करनेवालों जैसे—आरके धवन, मणिशंकर अय्यर, सतीश शर्मा, सुमन शर्मा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा आदि—को भरपूर सुविधा प्रदान करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, रेडियो-दूरदर्शन को चुनावी प्रचार-प्रसार का कारगर हथियार बना देना। शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को भी तिवारी की संभावित भूमिकाओं से कितनी आशा बंधी थी, यह उनकी तैनाती के दूसरे ही दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में मौजूद कांग्रेसियों के चमकते चेहरों और बातचीत में झलकते जोशखरोश से उजागर था। एक भूतपूर्व मंत्री ने टिप्पणी की, "जब तिवारी ने दूरदर्शन का मोर्चा संभाल लिया है, तो हम चुनाव अवश्य जीत जायेंगे।"

इस पर खरा उतरने में तिवारी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कमान संभालने के दस दिन के भीतर ही उन्होंने विभाग के समस्त केंद्र निदेशकों और समाचार संपादकों की मीटिंग बुलाकर सीधे-सीधे ताकीद की कि सरकार की उपलब्धियों का हरहाल गुणगान किया जाये। विशेषकर, जवाहर रोजगार योजना और पंचायत राज का। विपक्ष संबंधी समाचारों को ब्लैकआउट किया जाये। सिर्फ उनकी नकारात्मक खबरें दिखायी जायें। विभाग के एक उच्चाधिकारी ने 'माया' को बताया, "दूरदर्शन वैसे तो शुरू से ही सरकार और सत्तारूढ़ दल का हिमायती रहा है, किंतु हाल के निर्देशों ने इसे एकदम एकपक्षीय बना दिया है।"

'मुख्य समाचार वाचक': एकपक्षीय होने

यह आकाशवाणी नहीं राजीववाणी है
असत्यम् अशिवम् असुन्दरम् मूढदर्शन
T.V.

ऐसा पहली दफा: २५-२६ जून को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरोध प्रदर्शन

?: साठे

दूरदर्शन के लिए त्याज्य, विदेशी टीवी टीम के लिए ग्राह्य: बीपी सिंह

छाया: मनमोहन शर्मा

और सरकारी दखलंदाजी की एक नहीं, अनेक मिसालें मौजूद हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, वह दूरदर्शन पर हमेशा ही छाया रहा है। राजीव गांधी भी कभी इसका अपवाद नहीं बने। गद्दीनशीं होने के बाद से दूरदर्शन पर उनके प्रदर्शन में क्रमशः वृद्धि होती रही है। मई माह के दूरदर्शन समाचारों के विश्लेषण साक्षी हैं कि सर्वाधिक समय व लाइनें (८००) प्रधानमंत्री के खाते में गयीं। इसकी तुलना में द्वितीय स्थान ग्रहण करनेवाले गृह मंत्री बूटा सिह को मात्र १८० लाइनें मिलीं। समाचार के दौरान उनकी (राजीव गांधी) प्रमुख उपस्थिति के कारण स्वयं दूरदर्शन कर्मचारियों ने हंसी-हंसी में उन्हें 'मुख्य समाचार वाचक' की उपाधि दे डाली। किंतु पिछले कुछ दिनों में वे इस भूमिका से भी कहीं आगे निकल गये हैं। दूरदर्शन-रेडियो पर आज वे प्रमुख विपक्षीहंता भी हैं और पार्टी के चुनावी अभियान के मुख्य संचालक भी।

चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष पर उचित-अनुचित आरोपों की बौछार का एक भी मौका हमारे प्रधानमंत्री हाथ से नहीं जाने देते। विपक्ष पर कभी ठप्पा सांप्रदायिकता का लगाते हैं, तो कभी देश की प्रगति, सुरक्षा एकता-अखण्डता में बाधक होने का। यहां तक कि भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाने और देशद्रोह का परोक्ष संगीन इल्जाम भी बारंबार विपक्ष पर लगा उसकी छवि धूमिल करने का पूर्ण प्रयास रहता है। प्रधानमंत्री का विपक्ष की आलोचना कर उसे कटघरे में खड़ा करना नाजायज नहीं कहा जा सकता। किंतु विपक्ष को जवाब देने के अवसर से वंचित करना ठीक वैसा ही है, जैसे कि किसी अभियुक्त को अपनी सफाई के लिए कतई मौका न दे एकतरफा फैसला देना।

> दूरदर्शन का विपक्ष के प्रति सौतेला व्यवहार इसी से उजागर है कि मई के उपर्युक्त समाचार विश्लेषण के अनुसार जिस विपक्षी नेता को सर्वाधिक लाइनें (३७) प्राप्त हुईं, वे हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी जो विपक्ष से अधिक कांग्रेस के सगे माने जाते हैं।

दूरदर्शन का विपक्ष के प्रति सौतेला व्यवहार इसी से उजागर है कि मई के उपर्युक्त समाचार विश्लेषण के अनुसार जिस विपक्षी नेता को सर्वाधिक लाइनें (३७) प्राप्त हुईं, वे हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी जो विपक्ष से अधिक कांग्रेस के सगे माने जाते हैं। यद्यपि सूचना प्रसारण मंत्री भगत का दावा है कि दूरदर्शन विपक्ष को बराबर समय देता है, किंतु असलियत यह है कि विपक्ष की नाममात्र की खबरें दी जाती हैं और वे भी अधिकांशतः नकारात्मक।

हाल में सर्वाधिक हल्ला मधु लिमये के 'संडे मेल' में छपे जनता दल संबंधी लेख को लेकर मचा। दूरदर्शन-रेडियो ने चटपट उसके एक अंश (विपक्ष

प्रधानमंत्री
प्रतिदिन गला फाड़कर
दूरदर्शन पर विपक्ष को खालिस्तान
समर्थक और
विकास-विरोधी
कह रहे हैं, जबकि विपक्ष द्वारा
दिये गये आरोपों के
जवाब पर दूरदर्शन कभी आंख
उठाकर नहीं देखता।
प्रसिद्ध संविधान विद् सोली जे सोराबजी
का मत है कि श्रोता-दर्शक
को दूसरे पक्ष के विचारों से वंचित
रखना असंवैधानिक है।

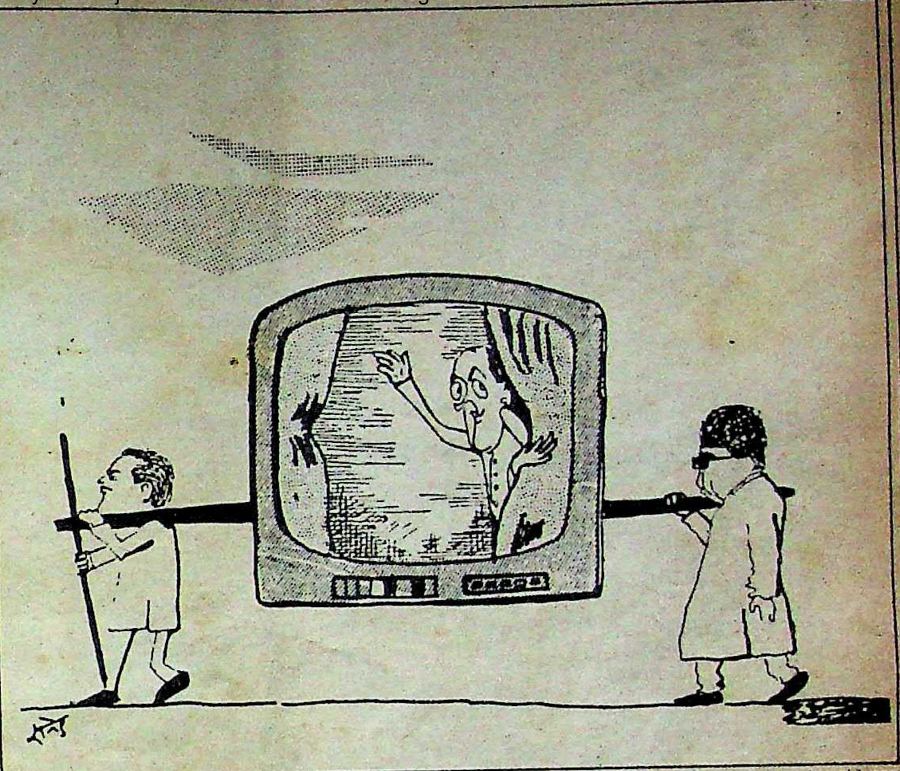

'जनसत्ता' से साभार

के विकल्प बनने और नेता के रूप में वीपी सिंह की खामियों) का धूमधड़ाके के साथ राष्ट्रीय प्रसारण किया। जब समाचारों में विचार (लेख) ठूंसने के इस अजूबे हथकंडे का व्यापक विरोध हुआ, तो सूचना प्रसारण राज्यमंत्री तिवारी ने सफाई दी, "हमने प्रकाशित लेख का प्रसारण किया है। मनगढ़ंत असत्य नहीं।" जवाब में लिमये 'माया' से बोले, "बात असत्य प्रसारण की नहीं 'अर्धसत्य' प्रसारित करने की है। उसे लेख के अनेक सकारात्मक, रचनात्मक पहलू भी थे, उन्हें क्यों नहीं चुना?" अपने उक्त लेख को संदर्भ से काट कर पेश किये जाने के खिलाफ लिमये ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित 'टाइम्स आफ इंडियां' को भी विरोध-पत्र भेजा और शिकायत दर्ज करायी है।

पक्षपात: जहां तक नकारात्मक खबरों का संबंध है, दूरदर्शन को इसमें विशेष महारत हासिल है। विपक्ष के मध्य घमासान निश्चित तौर से सरकारी मीडिया के लिए हरा चारा रहा है। जनता दल में विलय के मुद्दे पर जब लोकदल-ब स्व० हेमवतीनंदन बहुगुणा और दल के वरिष्ठ नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के बीच मतभेद और रस्साकशी जारी थी, तब बहुगुणा की प्रेस कांफ्रेंस कवर करने में दूरदर्शन ने कभी कोताही नहीं की, लेकिन देवीलाल उसकी इस अनुकंपा से वंचित रहे। इसी प्रकार स्वामी बनाम हेगड़े प्रकरण में दूरदर्शन ने स्वाभाविक रूप से डा० स्वामी को तरजीह दी।

दूरदर्शन की पक्ष-विपक्ष के संबंध में दोहरी नीति और उसके निम्न स्तर का सबसे ज्वलंत उदाहरण गत दिनों शाहजहांपुर की एक पार्टी में जनता दल महासचिव अजीत सिंह का कथित तस्कर नाजिर अली के साथ लिये गये चित्र का प्रसारण था। स्पष्ट संकेत-आरोप यही था कि विपक्ष और तस्करों की साठगांठ है। किंतु दिलचस्प बात यह थी कि तीन-चार दिनों बाद ही इसी नाजिर अली के साथ जब स्वयं राजीव गांधी के चित्र प्रकाशित हुए, तो उनका प्रसारण करना दूरदर्शन ने उचित नहीं समझा।

विपक्ष तो दरकिनार, विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक के समाचारों का प्रसारण करना भी दूरदर्शन को गवारा नहीं। कदाचित केके तिवारी के अनुसार, "पीएम (प्रधानमंत्री) तो न्यूज (समाचार) हैं और विपक्ष शासित राज्यों के सीएम (मुख्यमंत्री) फ्यूज (गुल) करने लायक हैं।" नतीजतन, विपक्षशासित राज्यों में इसका व्यापक प्रतिरोध है।

तमिलनाडु ने तो अपर्याप्त 'कवरेज' और पक्षपातपूर्ण रवैये के विरुद्ध संसद तक में आवाज उठायी है। द्रमुक सांसदों ने आरोप लगाया कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन को निर्देश दिया है कि करुणानिधि को दूरदर्शन पर दिखाने से परहेज किया जाये और यदि ऐसा संभव न हो, तो उनका 'क्लोजअप' न दिखाया जाये। तमिलनाडु में दूरदर्शन किस मुस्तैदी से इस हिदायत का पालन कर रहा था, वह इसी से उजागर है कि राज्य 'क्वाप्टेक्स' के एक विज्ञापन को दूरदर्शन ने प्रसारित करने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री का तीन सेकेंड का 'क्लोजअप' शामिल था। इन सबसे रुष्ट-असंतुष्ट मुख्यमंत्री करुणानिधि ने अपने कार्यक्रमों-प्रेस कांफ्रेंसों में दूरदर्शनवालों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल के साथ भी लगभग इसी प्रकार का हादसा तब हुआ, जब दूरदर्शन ने राज्य सरकार के बकटेश्वर के प्रस्तावित विद्युत कारखाने के एक विज्ञापन को प्रसारित करने से इनकार कर दिया। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है।

दूरदर्शन से चुनाव प्रचार: सरकारी मीडिया के 'उपयोग' को लेकर विपक्षी रोष-प्रतिरोध का सबसे बड़ा कारण उसे कांग्रेस के चुनावी प्रचार का माध्यम बना देना है। प्रधानमंत्री की नित्य प्रति की गतिविधियों-सम्मेलनों, उद्घाटन समारोहों, प्रेस कांफ्रेंस, यात्रा, प्रातःदर्शन और जनसभाओं—को नियमित रूप से छोटे परदे पर दिखाकर दूर-दराज की बहुसंख्य जनता से उनका सीधा साक्षात्कार कराया जा रहा है। इनमें विपक्ष की भरपूर भर्त्सना-आलोचना के अतिरिक्त वे (प्रधानमंत्री) अपनी योजनाओं-उपलब्धियों—जनता के हाथ सत्ता, जवाहर रोजगार योजना, 'अग्नि' का सफल परीक्षण, १८ वर्ष में मतदान का अधिकार, हरिजनों-गिरिजनों, व महिलाओं को आरक्षण आदि— का बखान अधिक करते हैं। यह निश्चय ही चुनावी युद्ध-पूर्व का वह शंखनाद है, जिसका लक्ष्य जनमत को अपने पक्ष में करना है। प्रधानमंत्री प्रतिदिन गला फाड़-फाड़कर दूरदर्शन पर विपक्ष को खालिस्तान-समर्थक और विकास-विरोधी कह रहे

टी.वी.-रेडियो
राजीव मां मत
लोकतंत्र की हत्यारी
कांग्रेस इ कांग्रेस इ
माया

बिना निष्पक्ष सूचना माध्यमों के लोकतंत्र अपाहिज है : एक प्रदर्शनकारी

छाया : पाना इंडिया

है, जबकि विपक्ष द्वारा दिये गये आरोपों के जवाब पर दूरदर्शन कभी आंख उठाकर नहीं देखता। प्रसिद्ध संविधानविद् सोली जे सोराबजी का मत है कि श्रोता-दर्शक को दूसरे पक्ष के विचारों से वंचित रखना असंवैधानिक है।

दूरदर्शन पर चुनाव अभियान मात्र प्रधानमंत्री ही नहीं चला रहे हैं, दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण सहायक हैं। सूचना मंत्रालय के ही एक अधिकारी के अनुसार, "किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण के निर्णय का मापदंड फिलहाल यही है कि सरकार, शासक दल और प्रधानमंत्री की छवि-सुधार में वह कार्यक्रम कितना सहायक होगा।" देशभक्ति के बहाने ऐसे कार्यक्रमों की भरमार की जा रही है, जिसमें नेहरू परिवार और उसके महान बलिदान, योगदान का भजन-कीर्तन अधिक हो। श्याम बेनेगल की साढ़े तीन करोड़ लागतवाली नेहरू की 'भारत एक खोज' पर बना ५२ कथांशों का सीरियल १४ नवंबर तक लगातार प्रसारित होता रहेगा। प्रातः टीवी पर 'नेहरू ने कहा था' दिखाया जा रहा है। मंजु सिंह का 'रिमेंबरिंग नेहरू' जुलाई में शुरू होगा। एमजे अकबर की नेहरू पर लिखी पुस्तक पर विनोद दुआ सीरियल बनाने में जुटे हैं। केनेथ ग्रिफिथ का नेहरू पर बनाया सीरियल भी जल्द प्रसारित होगा। कमला नेहरू पर केतन मेहता सीरियल बना रहे हैं। अशोक रैना नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखे पत्रों पर सीरियल तैयार कर रहे हैं। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आडवाणी बोले, "इस तरह के कार्यक्रमों की भरमार कांग्रेस का प्रचार और सामंती परिवारवाद के पोषण से अधिक कुछ नहीं। यह नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष अवश्य है। किंतु साथ ही आचार्य कृपलानी, मावलंकर और हेडगेवार का भी यही जन्म शताब्दी वर्ष है। तो सिर्फ एक (नेहरू) के इतने धुआंधार प्रचार-प्रसार का मतलब क्या है ?" रणनीति सीधे-सीधे यही है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और प्रगति का एकमात्र उत्तराधिकारी और संरक्षक प्रायोजित कर भरपूर चुनावी लाभ अर्जित किया जाये।

दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम भी चुनावी प्रचार रोग से मुक्त नहीं। राजनीतिक पर्यवेक्षक एमवी कामथ के अनुसार, "गत दो-तीन महीनों से सरकारी मीडिया सरकारी नजरिये को अधिकाधिक प्रचारित-प्रसारित करने में जुटा हुआ है। कारण, कदाचित वह नीतिगत मसौदा है जो उच्चाधिकारियों के मध्य हाल में वितरित किया गया है। इसमें ऐसे कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया है जो महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक भारतीय क्रांति की निरंतरता को दर्शायें। विभिन्न क्षेत्रों—कृषि, सिंचाई, बिजली, सुरक्षा, रेलवे आदि की उपलब्धियों के कार्यक्रम और वृत्त चित्रों के प्रसारण पर भी जोर दिया गया है। मसौदे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्कूली छात्रों, महिलाओं और ग्रामीण गरीबों से समूहों में की गयी मुलाकातों को भी समुचित रूप से दूरदर्शन पर दिखाया जाये। नतीजतन, फोकस, करेंट अफेयर्स से लेकर कृषि दर्शन, मजदूर और महिला जगत कार्यक्रमों तक में इसकी स्पष्ट छाया दिखायी देती है।

'फोकस' कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेनेवाले सीएस पंडित ने 'माया' को बताया, "पहले कम-से-कम एक-दो विपक्षी प्रवक्ताओं को भी बहस में बुलाया जाता था। किंतु अब उस प्रथा को भी ताक पर रख दिया गया है। दलील यह है कि वैसे भी आलोचना होती है। इसलिए टीका-टिप्पणी करने वालों को क्यों मौका दिया जाये।"

टीका-टिप्पणी से दामन बचाने का कितना अधिक प्रयास है, यह कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के तुरंत बाद इसी मुद्दे पर आयोजित 'फोकस' कार्यक्रम के संबंध में देखने को मिला। संयोग से कार्यक्रम में भाग लेनेवालों ने लगभग एक-सा रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने का पक्ष लिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रख्यात पत्रकार एस विश्वम ने 'माया' को बताया कि अंत में बहस का जायजा लेते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी

टी.वी.-रेडियो को
राजीव भोंपू मत बनाओ
लोकतंत्र की हत्यारी
कांग्रेस (इ) कांग्रेस (इ)
BJYM

छाया : पाना इंडिया

टीवी-रेडियो के जरिये कांग्रेस की उभरती छवि से चिंतित विपक्ष : भाजपा का विरोध प्रदर्शन

विषम क्यों न हों, किसी भी निर्वाचित सरकार के बहुमत का निर्णय विधानसभा की बैठक में ही होना चाहिए, राज्यपाल द्वारा नहीं। विश्वम का यह निष्कर्ष निश्चय ही केंद्र को कटघरे में खड़ा करने वाला था। अतः जब कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो अंत का लगभग डेढ़ मिनट लंबा यह हिस्सा फिल्म के संपादक की कैंचियों की भेंट चढ़ गया था। कदाचित यह भी मात्र संयोग ही था कि घटना ऐन उस दिन घटी, जिस दिन केके तिवारी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में पदभार संभाला था।

सरकारी शिकजा : प्रभावशाली दूरदर्शन के सामान्य कामकाज में वक्त-बेवक़्त की सरकारी दखलंदाजी सरकारी नीयत का भी परिचायक है और इस तथ्य का भी कि सत्ता पक्ष आगामी चुनाव और दूरदर्शन की भूमिका को कितनी अधिक अहमियत दे रहा है। दूरदर्शन की कड़ी निगरानी के लिए मंत्रालय के तीन मंत्रियों—भगत, तिवारी, कृष्ण कुमार—के अतिरिक्त सलाहकार के रूप में सुमन दुबे तो पहले से मौजूद ही थे, हाल में कैबिनट सचिवालय में बीएस देवधर भी मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त किये गये हैं। इन महानुभावों के अतिरिक्त दूरदर्शन की चौकसी का काम प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ उच्चाधिकारी—आरके धवन, मणिशंकर अय्यर, जी पार्थसारथी, सतीश शर्मा आदि भी कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि किस को कौन-से कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये, आज यह निर्णय भी दूरदर्शन के अधिकार क्षेत्र से निकलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय और विशेषतया प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है।

छोटे परदे पर दिखाये जानेवाले छोटे-बड़े कार्यक्रमों में हस्तक्षेप के अनेक किस्से मशहूर हैं। समाचारों पर विशेष गिद्ध दृष्टि रहती है। रात्रिकालीन ८.४० के हिंदी समाचार बुलेटिन के समाप्त होते ही समाचार कक्ष में बजनेवाली टेलीफोन की घंटी सबको आतंकित रखती है। कारण, अधिकांशतः निर्देश-संदेश ९.३० की अंग्रेजी बुलेटिन में काटने, जोड़ने का ही होता है। ताजातरीन मिसाल बंगलौर में पंचायती राज के क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रसारण की है। हिंदी समाचार के दौरान दिखायी गयी प्रधानमंत्री के भाषण की 'फिल्म क्लिप' में मंच पर बैठे कृषि मंत्री भजनलाल और युवा व खेल मामलों की मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा हंसते-बात करते दिखायी दिये थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में भृकुटियां तुरंत तन गयीं। कारण उक्त क्लिप से प्रचार की जगह कुप्रचार होने की अधिक संभावना थी, क्योंकि उससे यह आभास हो सकता था कि मंत्रियों को दिलचस्पी प्रधानमंत्री के भाषण से अधिक हंसी-मजाक में थी। अतः उसे अगले अंग्रेजी समाचार बुलेटिन से काट देने का फरमान फौरन जारी कर दिया गया।

जोड़ने का काम भी इसी मुस्तैदी से किया जाता है। कमला बहुगुणा और बीपी मौर्य के कांग्रेस में शामिल होने के फौरन बाद दूरदर्शन ने उन्हें हाथो-हाथ लिया। किंतु अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मौर्य द्वारा देवीलाल पर पार्टी सदस्यों-विधायकों की खरीद-फरोख्त के गंभीर आरोपों को हिंदी समाचारों में शामिल करना उचित नहीं समझा। उक्त 'भूल सुधार' का काम तब हुआ, जब मंडी हाउस के उच्चाधिकारियों के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का हुक्मनामा पहुंचा। नतीजतन, बाद में प्रसारित अंग्रेजी समाचारों में मौर्य को उनके सारे-के-सारे आरोपों सहित दर्शाया गया।

रेडियो भी इस प्रकार के हस्तक्षेपों और दिशानिर्देशों से परे नहीं है। १५ जून को आकाशवाणी पटना के स्टाफ को इसका भरपूर स्वाद तब मिला, जब प्रधानमंत्री की उसी दिन वहां आयोजित पार्टी रैली के सिलसिले में निर्देश स्वयं सूचना प्रसारण राज्यमंत्री तिवारी ने दिये। मंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार क्षेत्रीय समाचारों में राजीव गांधी की एकमुश्त औद्योगिक योजना को रात साढ़े सात बजे के बुलेटिन में सर्वोपरि स्थान देना था। चूंकि निर्देश अंतिम क्षणों में मिला था, इसलिए उसे लागू करना संभव न हुआ। इस पर

तिवारी आगबबूला होकर 'देख लेंगे' के अंदाज में आ गये।

मजबूरी: इलेक्ट्रानिक मीडिया पर कसते सरकारी शिकंजे की अपनी विवशता है। सर्वप्रथम यह कि शासक दल के एकमात्र अखिल भारतीय पहचान और प्रभाववाले नेता राजीव गांधी चुनाव पूर्व शहर-शहर, गांव-गांव जाकर मतदाताओं से बेखटके रूबरू नहीं हो सकते। कारण, उनकी सुरक्षा का संगीन मसला है। ऐसी स्थिति में दूरदर्शन के जरिए वे अत्यधिक सहज, शीघ्र और कारगर ढंग से घर-घर जाकर अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं।

आपातकाल की ज्यादतियों की कालिमा को आज तक धो सकने में असमर्थ तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ल मीडिया के दुरुपयोग के पीछे गंभीर विपक्षी चुनौती, पार्टी (कांग्रेस) की गुटबंदी और आम कार्यकर्ताओं का अभाव देखते हैं। इसके अलावा आक्रामक तेवरवाला प्रेस भी दरपेश है। ऐसी स्थिति में एकमात्र साधन उनके पास यही है कि दूरदर्शन और रेडियो को प्रचार-प्रसार की मशीन बना दें।

इंदरकुमार गुजराल एक कदम आगे बढ़ वर्तमान परिदृश्य में उसी हताशा, निराशा और चिता की झलक देखते हैं, जिसने जेपी आंदोलन के दौरान श्रीमती गांधी को घेर लिया था। गुजराल ने उन दिनों का स्मरण करते हुए 'माया' को बताया, "श्रीमती गांधी ज्यों-ज्यों जेपी आंदोलन के वेग और प्रभाव मे अक्षम-अशक्त होती गयीं, त्यों-त्यों उन्होंने रेडियो पर अपना दबाव बढ़ाया। चूंकि उनके इर्द-गिर्द के लोगों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आकाशवाणी संकटमोचन साबित हो सकती है। उस समय मैंने श्रीमती गांधी को पत्र लिखकर सलाह दी थी कि जेपी आंदोलन से आकाशवाणी नहीं, पार्टी कार्यकर्ता ही लोहा ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरी सलाह नही मानी।"

अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं के सरकार विरोधी रवैये के कारण रेडियो-दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यमों का सहारा लेने की बात दूरदर्शन को अपने सूचना प्रसारण मंत्रित्वकाल मे अभूतपूर्व विस्तार-प्रसार देनेवाले वर्तमान ऊर्जा मंत्री वसंत साठे भी स्वीकारते हैं। 'माया' से एक विशेष भेंट में उन्होंने कहा, "विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, घोषणाओ के लिए दूरदर्शन-रेडियो का उपयोग करना मेरी समझ में न तो अनुचित है, न अनैतिक न अवैधानिक। विपक्ष के पेट में इसलिए दर्द है कि उन्हें अपने एकसूत्री 'राजीव हटाओ' कार्यक्रम को दूरदर्शन से प्रसारित करने की सुविधा नहीं। यदि उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम या सकारात्मक आलोचना हो—जैसे वे यह कहें कि पंचायत राज, जवाहर रोजगार योजना क्यों नहीं लागू होनी चाहिए—तो हम दावे से यह कह कसते हैं, उसका प्रसारण होगा। लेकिन यह कहे कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, किंतु उसे जनता तक न पहुंचाये, क्योंकि उससे आप लोकप्रिय होंगे, तो यह कोई दलील नहीं।"

"विपक्ष अभियान का मुख्य लक्ष्य अपने घर में मचे घमासान से लोगों का ध्यान बंटाना है। साथ ही, अपनी घटती लोकप्रियता से वंचित विपक्ष इस आंदोलन के सहारे अपना पैर जमाना चाहता है।"

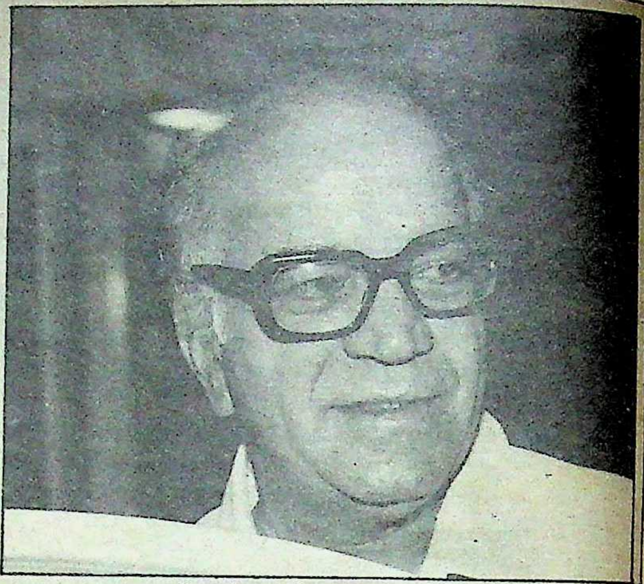

विपक्ष बेवजह शोर करता है: गाडगिल

कितने वोट दिलायेगा दूरदर्शन ?

जब राजीव गांधी को दूरदर्शन के परदे पर राजस्थान या तमिलनाडु में किसी गरीब परिवार से मिलते-बतियाते दिखाया जाता है, तब उसे ४१ करोड़ मतदाताओं या साढ़े ८३ करोड़ की आबादी में से कितने लोग देखते हैं ? किसी ने यह संख्या गिनी नहीं है, न ही इसकी सही-सही गणना की जा सकती है। दूरदर्शन ने दर्शकों के कुछ सर्वेक्षण जरूर किये हैं और समय-समय पर वह कुछ नमूनों के आधार पर ऐसा करता ही रहता है। लेकिन दूरदर्शन के इस गणित पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह से सही नतीजा मिल ही नहीं सकता। इस बारे में एक मोटा हिसाब लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही देखना है कि एक ही समय दूरदर्शन का कार्यक्रम देखनेवालों की संख्या कितनी है। इसके लिए दो मोटी बातों का पता चलना जरूरी है: पहली, दूरदर्शन-दर्शकों की औसत संख्या और दूसरी, चलनेवाले टीवी सेटों की कुल संख्या।

मान लें कि एक परिवार में औसतन पांच आदमी होते हैं (औसत गृहस्थी का यही आकार सरकार मानती है), तब उस घर के दूरदर्शन को उतने लोग तो देखेंगे ही, उनके कुछ अतिथि या दूसरे घरों के कुछ लोग भी देखेंगे। अब यदि यह माना जाये कि एक घर में, एक साथ दूरदर्शन देखनेवालों की संख्या, घर के सदस्यों की पांचगुनी है, तब टीवी देखनेवालों की कुल संख्या, चालू हालतवाले टीवी सेटों की संख्या की पांच गुनी हुई। इस हिसाब से दूरदर्शन के दर्शकों की कुल संख्या ५ और साढ़े ७ करोड़ के बीच आती है।

एक अनुमान के अनुसार दुरुस्त और चालू दूरदर्शन सेटों की कुल संख्या ६० लाख है। दूसरे छोर के एक अनुमान से ऐसे टीवी सेटों की संख्या २ करोड़ है। वास्तव में ऐसे टीवी सेटों की अधिकतम संख्या १.५ करोड़ से बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। देश में अब तक लगभग १.६ करोड टीवी सेट तैयार किये गये हैं। '२०' श्याम-श्वेत वहनीय सेटों और रंगीन टीवी सेटों की कुल संख्या यही है। इनमें दस फीसदी शुद्ध निर्यात (अर्थात कुल निर्यात ऋण आयात) वाले हैं और दूसरे दस फीसदी बेकार हो गये हैं, उनकी जगह नये सेटों ने ले ली है। फिर कम-से-कम ५ लाख टीवी सेट बिना बिके पड़े हैं, बच जाते हैं, लगभग १.५३ करोड़ सेट। उनमें से सब घरों में ही नहीं लगे हैं। कुछ स्कूल-कालेजों में लगे हैं, तो कुछ कार्यालयों तथा दूसरी-दूसरी संस्थाओं में। इस प्रकार लोगों के घरों में लगे टीवी सेटों की कुल संख्या १.५ करोड़ से ज्यादा नहीं ठहरती। इसे पांच गुना कर देने पर कुल दर्शकों की संख्या बनती है, साढ़े ७ करोड़।

कितु ऐसे भी लोग हैं, जिनके घर टीवी नहीं है और जो दूसरी जगहों पर टीवी देखते हैं। देहात में ऐसे ढेर सारे लोग हैं। अब यदि यह माना जाये कि गांव में एक टीवी को औसतन ३० लोग देखते हैं, तो जाहिर है कि गांवों में (जहां २० लाख टीवी सेट लगने का अनुमान है) दूरदर्शन देखनेवालों की संख्या करीब ६ करोड़ है। यह तभी संभव है, जब गांवों में बिजली की आपूर्ति होती हो। पर सचाई

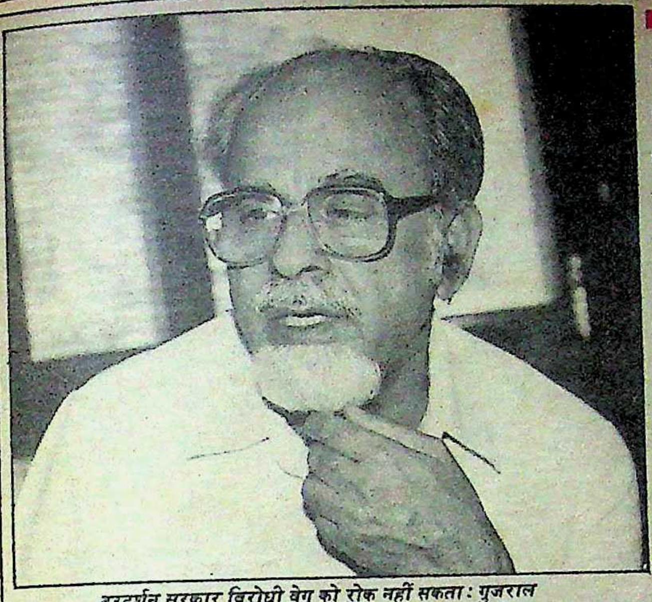

दूरदर्शन सरकार विरोधी वेग को रोक नहीं सकता : गुजराल

> **"उस समय मैंने श्रीमती गांधी को पत्र लिखकर सलाह दी थी कि जेमी आंदोलन से आकाशवाणी नहीं, पार्टी कार्यकर्ता ही लोहा ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी।"**

यह है कि देहात में बिजली की आपूर्ति प्रायः 'अगर-मगर' में ही फंसी-रुकी रहती है। शहरी इलाकों में भी, जहां अनुमानतः १३० लाख टीवी सेट लगे हैं और एक सेट पर औसतन ६ दर्शक हैं, दर्शकों की कुल संख्या ८ करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती।

इस तरह टीवी दर्शकों की कुल तादाद १४ करोड़ हुई। इसमें से १८ साल से कम उम्रवालों की संख्या कुल दर्शक-संख्या की कम-से-कम एक तिहाई है। शेष बचते हैं करीब ९.४ करोड़—देहात में ४ करोड़ और शहरों में ५.४ करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण मतदाताओं (करीब ३० करोड़) में एक बटे सात से भी कम और शहरी मतदाताओं (लगभग ११ करोड़) में दो-तिहाई लोग ही, देश का दौरा करते राजीव गांधी को या १, सफदरजंग रोड में पड़े स्व० इंदिरा गांधी के शव के १९८४ वाले नजारे को देख सकते हैं। यह भी कार्यक्रम की लोकप्रियता, उसके समय और साथ ही इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यक्रम-प्रसारण के समय कितने स्थानों पर बिजली की आपूर्ति होती है। अधिक-से-अधिक दर्शकों के लिए ये सभी संयोग-सुविधाएं जुट जायें, यह बहुत मुश्किल है। शहरों में, चूंकि देहात के मुकाबले बिजली की आपूर्ति बेहतर रहती है इसलिए, टीवी को अधिक समय तक चलाया जा सकता है।

एक खतरा भी है। दूरदर्शन देखनेवालों पर विज्ञापनों और फीचर फिल्मों का असर भी कम नहीं होता। ये चीजें, गरीब या महंगी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ आदमी के मन में बेहतर जिंदगी की आकांक्षाएं जगा देती हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरक के विज्ञापन में प्रदर्शित किसान के कपड़े अच्छे और चमचमाते होते हैं, उसकी पत्नी रंगीन और महंगी साड़ी पर बेशकीमती सुनहरे जेवर पहने होती है। स्वभावतः, विज्ञापन देखनेवाले किसान और उसकी पत्नी की इच्छा भी वैसी ही हो जाती है, हालांकि खेती से होनेवाली आय से ऐसी चीजें हासिल की ही नहीं जा सकतीं। वास्तविक जीवन में 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' वाली विडंबना है और किसान इस तल्ख सचाई को जानता है कि सरकार ने उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। इसलिए बहुत संभव है कि टीवी देखनेवाले किसान, न देखनेवालों की तुलना में अधिक असंतुष्ट हो जायें। इनमें से कुछ किसानों में तो दूरदर्शन काफी असंतोष और आक्रोश भड़कानेवाला है और चुनाव-पूर्व के प्रचार इस असंतोष-आक्रोश का शमन नहीं कर सकते।

ऐसे मामलों में दूरदर्शन सुविधा-साधन से कहीं अधिक भार बन जा सकता है। कम-से-कम दो-तिहाई शहरी दर्शक उतने ही असंतुष्ट हैं जितने किसान हैं। एक ओर, ये लोग भारी मकान किराये, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मारे हैं, तो दूसरी ओर टीवी ने इनकी आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं।

पिछले अनुभव याद दिलाते हैं कि सहानुभूति की लहर और दूरदर्शन की भरपूर भूमिका के बावजूद राजीव गांधी की पार्टी १९८० में पड़े वोटों में से आधा भी नहीं पा सकी। आधे से अधिक लोगों ने कांग्रेस-इ के विरुद्ध मतदान किया। इस हकीकत के बावजूद राजीव गांधी के दरबारी यदि इस 'दृश्य माध्यम' पर बहुत ज्यादा भरोसा किये बैठे हैं, तो यह उनकी बलिहारी ही है। कौन जानता है कि वे जो खोयेंगे, उससे अधिक पायेंगे ही?

—कुमारेश चक्रवर्ती

कांग्रेसियों का मानना है कि विपक्ष का वर्तमान दूरदर्शन-रेडियो विरोधी अभियान मात्र चुनाव प्रेरित और राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से चलाया गया है। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री व कांग्रेस महासचिव विट्ठल नरहरि गाडगिल के अनुसार, "विपक्षी अभियान का मुख्य लक्ष्य अपने घर में मचे घमासान से लोगों का ध्यान बंटाना है। साथ ही, अपनी घटती लोकप्रियता से चिंतित विपक्ष इस आंदोलन के सहारे अपना पैर जमाना चाहता है। विपक्ष इलेक्ट्रानिक मीडिया की स्वायत्तता की मांग करते हुए जिस बीबीसी की दुहाई दे रहा है, वह बीबीसी भी विदेशी मामलों में कुछ स्वतंत्र अवश्य है, राष्ट्रीय मामलों में नहीं।"

उल्लेखनीय है कि जनता दल ने इलेक्ट्रानिक मीडिया संबंधी अपनी घोषित नीति में कहा है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को संसद के घोषणा-पत्र के अधीन स्वायत्तशासी निगम बनाया जायेगा। इसके लिए गवर्नरों का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा और इसका प्रबंध पेशेवर लोगों द्वारा किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत संगठन के दायरे में उन्हें संघीय और स्थानीय स्वायत्तशासी अधिकार होंगे और वे परामर्शदात्री कार्यक्रम समितियों के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे और वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। साथ ही प्रचार मीडिया का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण और सभी आयु-वर्ग के लोगों के लिए भाषा सीखने के लिए सशक्त साधन के रूप में किया जायेगा। पिछले तीन वर्षों में मूल्यों में आयी चिन्ताजनक गिरावट से बचने के लिए मानक परिषद की स्थापना की जायेगी। यह मानक परिषद, प्रसारण निगम और सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहेगी। जनता की शिकायतें भी इस परिषद के समक्ष रखी जायेंगी। परिषद दूरदर्शन और रेडियो से सम्बन्ध रखनेवाले सभी लोगों के काम पर नजर रखेगी, उनकी सहायता करेगी और स्तर ऊंचा उठायेगी।

"कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है," गाडगिल बोले, "ऐसी ही घोषणा जनता पार्टी ने १९७७ में सत्तारूढ़ होने के पूर्व अपने चुनाव घोषणापत्र में की थी। किंतु उस पर अमल करना दूर, दूरदर्शन-रेडियो का जितना दुरुपयोग जनता शासनकाल में हुआ, उतना कभी और नहीं। अतः विपक्ष के मुंह से स्वतंत्रता, स्वायत्तता की बात शोभा नहीं देती।" केके. तिवारी ने जोड़ा, "रेडियो-दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने का वायदा करनेवाली जनता सरकार ने वर्गीस समिति नियुक्त करने के बावजूद उसकी सिफारिशों को ताक पर रख दिया था। तीन साल के अपने कार्यकाल में उसने स्वायत्तता विधेयक पास करने की कोई कोशिश नहीं की। जहां चाह होती है, वहां राह होती है। हमने पंचायत राज विधेयक एक दिन में पास कर दिया है। जनता सरकार के सूचना-प्रसारण मंत्री फासिस्ट आडवाणी ने दूरदर्शन रेडियो को बंधक बना, उस पर अपना शिकंजा कसने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं को भरने के अतिरिक्त कुछ और नहीं

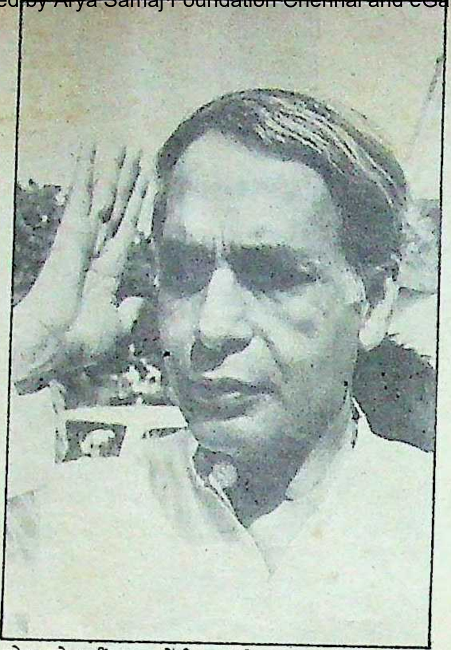

लोग भूले नहीं: इमरजेंसी-काल के सूचनामंत्री विद्याचरण शुक्ल

किया।"

जवाब में आडवाणी बोले, "आज तक आरोप मुझ पर अति उदार होने का लगता रहा है। निखिल चक्रवर्ती को जब मैंने प्रेस कौंसिल में शामिल किया, तो श्री चक्रवर्ती के कम्युनिस्ट समर्थक होने से लोगों ने मेरा बड़ा विरोध किया था। किंतु मैंने अपना निर्णय बदला नहीं था। हम किसी भी खबर को 'ब्लैक आउट' नहीं करते थे। यहां तक कि राजनारायण जो हमारी ही पार्टी की जड़ खोद रहे थे, की खबर भी प्रसारित की जाती थी।" आडवाणी इसका भी खंडन करते हैं कि जनता शासनकाल में कुछ किया ही नहीं गया, "हमने पहली बार विधानसभा चुनाव से पूर्व हर पार्टी को अपना कार्यक्रम-विचार रेडियो-टीवी से प्रसारित करने का समान अवसर प्रदान किया, जिसके खिलाफ पिछले २० साल से कांग्रेस लगातार अड़ंगे लगाती रही थी। इसी प्रकार संसद को कवर करनेवाले संवाददाताओं को रक्षाकवच प्रदान करने वाले फीरोज गांधी एक्ट को, जिसे श्रीमती गांधी ने रद्द किया था, न सिर्फ बहाल किया, बल्कि संवैधानिक स्वरूप दिया। श्रीमती गांधी द्वारा समाप्त प्रेस कौंसिल विधेयक को भी हमने बहाल किया जो आज भी लागू है। यदि तीन महीने का समय राजनारायण ने हमारी सरकार को और दिया होता, तो हम स्वायत्तता विधेयक (मीडिया) भी पारित कर देते।" जनता पार्टी शासनकाल में नहीं पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ भी उसके खुलेपन की नीति का परिचायक मानी जाती है।

आरोपों-प्रत्यारोपों की बाढ़ में अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकारी मीडिया को पूर्ण स्वायत्तता कोई भी सरकार देना पसंद नहीं करेगी। सीएस पंडित का यह भी कहना है, "हर सरकार इस प्रभावशाली माध्यम का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है। फर्क इतना है कि कुछ यह काम नफासत से करती हैं, तो कुछ वर्तमान सरकार की भांति बड़े भोंड़े ढंग से।

हानि या लाभ ? : प्रश्न यह है कि इस समय मीडिया का चुनावी प्रचार कार्य में जो अधिकाधिक उपयोग हो रहा है, क्या वह फलदायी होगा? सरकार ने दृश्य-श्रव्य माध्यम के व्यापक और दूरगामी प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए ही धुआंधार चुनावी प्रचार के लिए इसको एक हथियार बनाया है। इसी भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन प्रसारण के मौजूदा १४ घंटे को बढ़ा कर

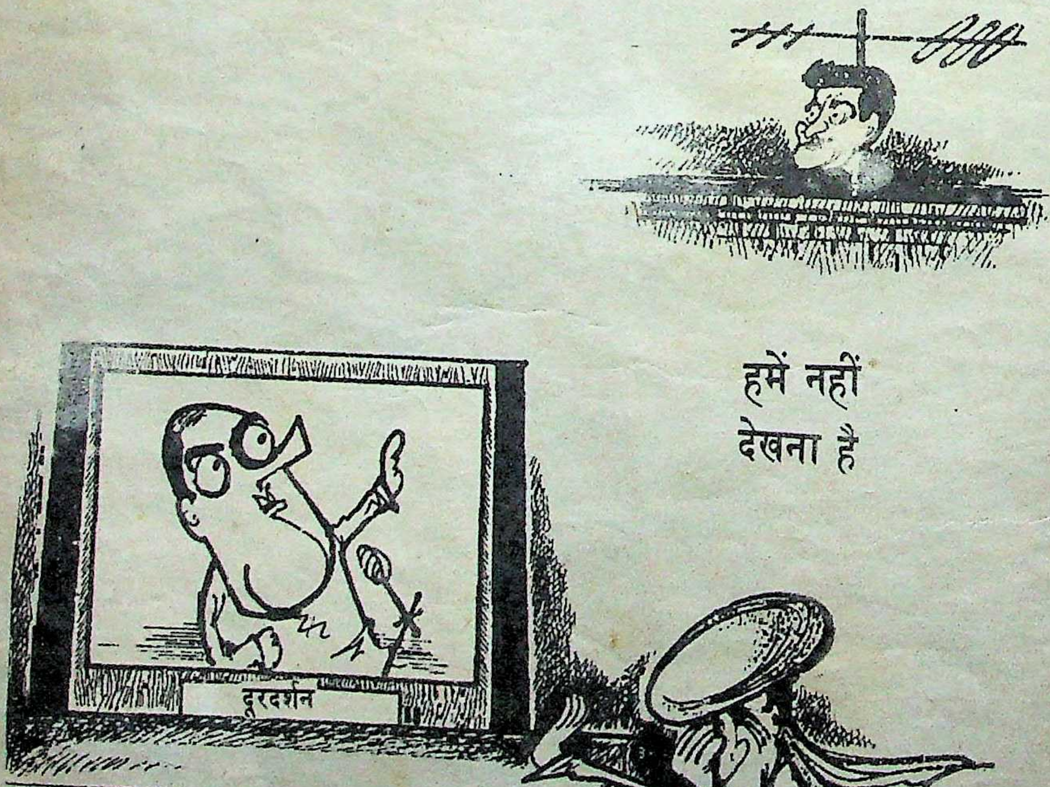

'इंडियन एक्सप्रेस' से साभार

शीघ्र १८ घंटे करने की योजना बनायी जा रही है। साथ ही चूंकि आज हर सांसद-विधायक अपने क्षेत्र में कुएं की जगह टीवी टावर बनाने का आग्रह कर रहा है, इसलिए हर निर्वाचन क्षेत्र में टीवी टावर बनाने का वायदा और काम भी शुरू कर दिया जाये, तो आश्चर्य नहीं। दूरदर्शन पर चुनावी प्रचार-प्रसार के हवन में २०० करोड़ रुपए स्वाहा होंगे, ऐसा भी जानकार सूत्रों का दावा है। वैसे इन सभी मंसूबों पर राष्ट्रीय प्रसारण के परमावश्यक माध्यम-नये इनसेट (वन डी) की हाल की विफलता ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। किंतु मात्र इस कारण सरकार अपने चुनावी अभियान की गाड़ी रुक जाने देगी, इसकी संभावना नहीं। दूरदर्शन अधिकारियों के अनुसार पहले तो इनसेट में उत्पन्न खराबी पर समय रहते काबू पा लिया जायेगा अन्यथा या तो अन्य प्रसारण साधन जैसे माइक्रोवेव का उपयोग होगा अथवा अमरीका-सोवियत संघ से प्रसारण माध्यम की व्यवस्था की जायेगी।

किंतु वांछित लाभ की पहली शर्त विश्वसनीयता है। इसकी सरकार और सरकारी मीडिया में कमी है, ऐसा जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह का मानना है। उन्होंने 'माया' से कहा कि हमारी बात अब जनता के बीच पहुंच चुकी है। 'इडियट बाक्स' (टेलीविजन) किसे इडियट (बेवकूफ) बनायेगा, यह चुनाव बाद खुदबखुद सामने आ जायेगा। अरुण नेहरू ने जोड़ा, "दूरदर्शन की विश्वसनीयता तो तब खरी उतरती, जब प्रधानमंत्री की जनसभाओं की भांति वह वीपी सिंह की जनसभा का प्रसारण करता। ऐसा वे इस डर से नहीं करते कि दोनों का फर्क पलक झपकते जगजाहिर हो जायेगा।"

विश्वसनीयता की कमी की बात सुनते ही साठे बोले, "यह आरोप पंचसितारा होटल में बैठकर दूर की हांकनेवालों का है। जहां तक जनमत का सवाल है, ऐसे लोगों का मत अर्थ ही नहीं रखता। कारण वे न तो मतदान करते हैं, न अपने सीमित संकुचित दायरे के बाहर मत-प्रदर्शन। आम जनता में हमारी साख बरकरार है।" जनता की साख सचाई के साक्षात्कार से होती है, नकली प्रदर्शन प्रसारण से नहीं। मसलन, आपरेशन ब्लैक थंडर मुहिम का दूरदर्शन पर जब प्रसारण हुआ, तो पंजाब में भरपूर जनसमर्थन हासिल हुआ। विपरीत परिणाम तमिलनाडु विधान सभा चुनाव मे निकला। स्थानीय दूरदर्शन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु यात्राओं तथा कांग्रेसी रैलियों सभाओं का धुआंधार प्रसारण करने के बावजू मतदाताओं को रिझाने-मनाने में विफल रहा। उपर्युक्त दोनों मिसालें सिद्ध करती हैं कि भारती मतदाता अनपढ़ भले हैं, अमानी नहीं। नीर-क्षी विवेक से परिपूर्ण हमारा मतदाता दूरदर्शन क दर्शन तो आंख से अवश्य करेगा, पर फैसल दिलोदिमाग से।

—रंजना कक्क

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के सा

दूरदर्शन

भीमकाय विस्तार

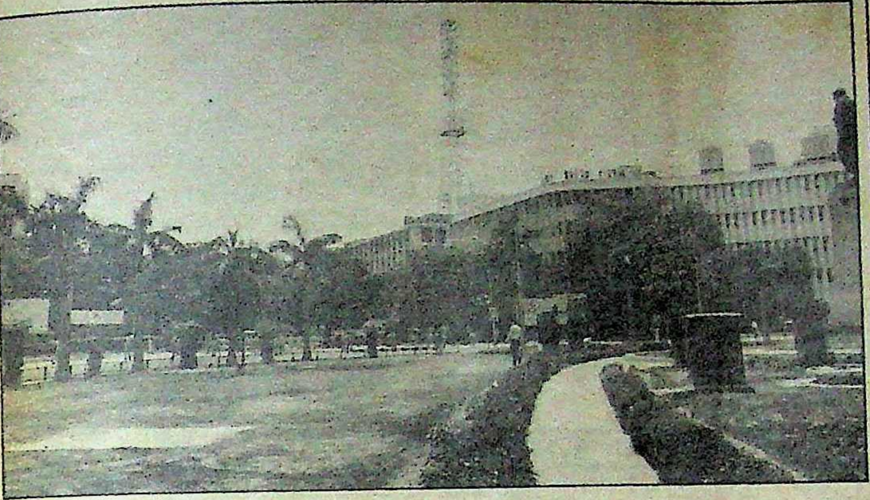

आधुनिक तकनीकी उपलब्धि—रेडियो-दूरदर्शन-ने जनमानस तक सूचना-संदेश पहुंचाने और जनमत बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभायी है। हल जोतते किसान के कंधे से लटकता ट्रांजिस्टर दृश्य आज कोई अजूबा नहीं। आज गांवों की चौपालों में हुक्कों के इर्द-गिर्द लगनेवाली बैठकें बिजलीयुक्त सामुदायिक विकास केंद्रों अथवा पंचायत घरों में लगे टीवी सेट के सामने लगने लगी हैं। रेडियो-टेलीविजन के हाथ कितने लंबे हैं, यह इसी से जाहिर है कि देश का ९५ प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पुराने सूचना माध्यम रेडियो प्रसारण की परिधि में है। नवागत दूरदर्शन भी खास पीछे नहीं। उसकी पहुंच देश के लगभग ७० प्रतिशत क्षेत्र तक हो गयी है।

पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में १९५९ में खुला। अगला स्टेशन (बंबई के) खुलने में १३ वर्ष लग गये। १९७२ और १९८२ के बीच पांच और स्टेशन कलकत्ता, मद्रास, जालंधर, लखनऊ व श्रीनगर में खुले।

१९८२ में सूचना-प्रसारण मंत्री वसंत साठे के कार्यकाल में दूरदर्शन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। पहली बार देश में 'लो पावर ट्रांसमिशन' (एलपीटी) का शुभारंभ हुआ। १५ अगस्त, १९८२ को इस क्षेत्र में तीन नये आकर्षण जुड़े। पहला रंगीन टेलीविजन, दूसरा इंसेट और तीसरा राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम। उसी १५ अगस्त को ४१ ट्रांसमीटरों से श्रीमती गांधी के लाल किले से दिये गये भाषण का राष्ट्रव्यापी प्रसारण हुआ।

१९८४ दूरदर्शन के भीमकाय विस्तार के दूसरे चरण का साक्षी बना। सितंबर-अक्तूबर के बाद यह विस्तार इतना तीव्रगामी रहा कि हर रोज कम-से-कम एक नया ट्रांसमीटर स्थापित हुआ। इसने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। १९८२ में लक्ष्य यदि एशियाड था, तो १९८४ में आगामी चुनाव। यही कारण है कि श्रीमती गांधी की शहादत छोटे परदे से होती हुई देशवासियों के हृदय में बस गयी और राजीव गांधी की झोली वोटों से भर गयी।

विस्तार की यह रफ्तार १९८४ के बाद भी बरकरार रही। नतीजतन १ अप्रैल '८९ को देश में ३५५ ट्रांसमीटिंग स्टेशन हो गये और दूरदर्शन केंद्रों की संख्या ७ से बढ़कर १८ हो गयी। मार्च १९९० तक कुल ५३३ ट्रांसमीटिंग स्टेशन हो जायेंगे।

आकाशवाणी :

आकाशवाणी का विस्तार भी तेजी से हुआ। १९८० और १९८८ के आंकड़े इसके गवाह हैं:

	१९८०	१९८८
कुल प्रसारण केंद्र	८४	९६
रेडियो की कुल आबादी तक पहुंच	९०%	९५%
रेडियो की कुल क्षेत्र तक पहुंच	७८%	८३%

निरक्षरता के रोग से अभिशप्त भारत के लिए इन संचार माध्यमों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कारण, वर्णमाला की अनभिज्ञता को दृश्य-श्रव्य का यह अभूतपूर्व संसाधन जनता की आंख और कान बन पृष्ठभूमि में डाल देता है। ■

साक्षात्कार : केके तिवारी

चुनाव परिणाम सिर्फ रेडियो-टीवी तय नहीं करते

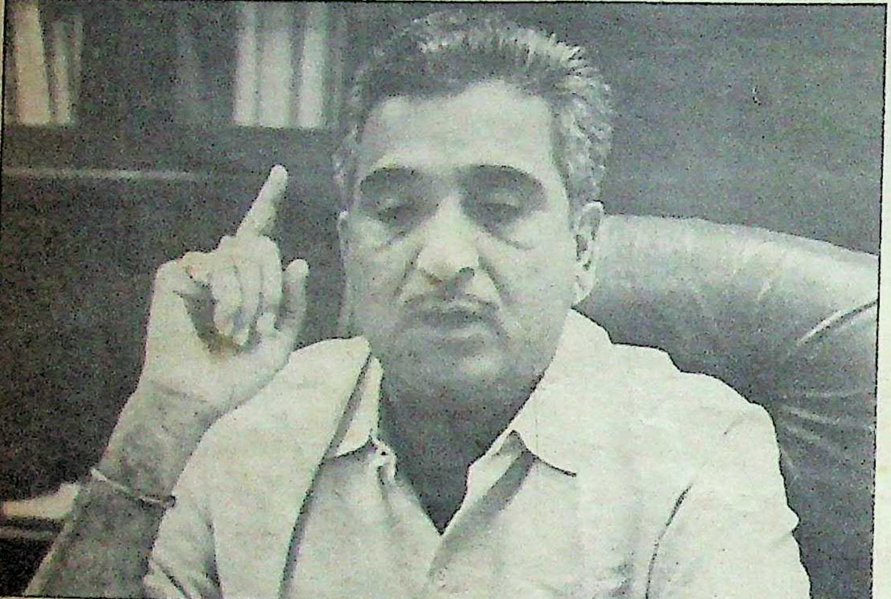

लोकसभा में बक्सर (बिहार के प्रतिनिधि उनचास वर्षीय प्रो० केके तिवारी जब अपने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हैं, तो फिर उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। सूचना मंत्रालय में केके तिवारी के राज्यमत्री बनकर आने के बाद दूरदर्शन और रेडियो के रवैये पर विपक्ष में मचे हाहाकार के संबंध में साक्षात्कार के लिए वे रंजना कक्कड़ से बिना हीलहुज्जत के मिले, लेकिन जब उन्होंने धाराप्रवाह बोलना शुरू किया, तो उन्हें एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक लाना खासा मुश्किल हो गया। दूसरी परेशानी उन शब्दों ने पैदा की जो वे विपक्षी नेताओं के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 'क्या लिखूं, क्या छोड़ूं' के संशय से निकलने के बाद रंजना कक्कड़ ने यही तय किया कि मंत्री और पाठक के बीच वे वैसी बाधा न बनें, जैसी टीवी-रेडियो के दर्शक-श्रोता के बीच बाधा बनने का आरोप श्री तिवारी पर लगाया जाता है। इसलिए प्रस्तुत हैं 'माया' के सवाल और श्री तिवारी के जवाब ज्यों-के-त्यों :

माया : आम धारणा है कि दूरदर्शन के जरिये विपक्ष की छवि धूमिल करने और विपक्षी नेताओं के चरित्रहनन के लिए आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लाया गया है।

केके तिवारी : *सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप लोग राजनीति के शिकार हो गये हैं। पहली बात इस चुनावी लड़ाई को हम कोई मौलिक लड़ाई नहीं मानते। कारण हम चुनावी अथवा मौसमी पार्टी नहीं। विपक्षी पार्टियां मौसमी बीमारियों की तरह हैं। दुनिया की हरेक जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जिस दिन बनती है, उसी दिन विपक्ष की भी भूमिका शुरू हो जाती है। उसकी भी 'शैडो' सरकार बन जाती है। यदि सत्तारूढ़ पार्टी किसी तरह शासन नहीं चला सकती, तो विपक्ष इसके लिए तैयार रहता है। इस प्रकार विकल्प उसी दिन तैयार हो जाता है और लगातार पांच साल चलता है। केवल भारत ऐसा देश है, जहां चुनाव की गंध आते ही राष्ट्रीय विकल्प बनता है। हम चुनाव को न अपनी शुरुआत मानते हैं न अंत। कारण हमारी दुनिया की सबसे बड़ी, लोकतांत्रिक और इंकलाबी पार्टी है।*

माया : बात पार्टी की नहीं, आपकी छवि की है।

तिवारी : *हमारी (मेरी) भूमिका व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। हम पार्टी के एक अदना सिपाही, कार्यकर्ता हैं। हम कोई चिरकुटी पार्टी नहीं। भारत को स्वाधीनता दिलानेवाली, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बुलंदियों पर पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। हम कोई भगोड़े नहीं, दलबदलू, प्रपंची, ठग नहीं हैं, जैसा वीपी सिंह है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसने अपनी आत्मा ही बेच दी है। विपक्ष का खोखलापन देखिए कि ४० साल से कोई विकल्प देने की जगह उस आदमी के पास गये जो कांग्रेस का भगोड़ा है। एक सामंती व्यक्ति, जिसने कांग्रेस की पूरी समाजवादी व्यवस्था को अपने बजट से बर्बाद कर दिया था। हमारी गरीब समर्थक छवि को चौपट कर दिया था। यही मधु दंडवते वीपी सिंह के वित्त मंत्री-काल में उनके खिलाफ मोटा पुलिंदा लेकर राष्ट्रपति के पास गये थे। लोकदल-अ और लोकदल-ब ने भी उप्र के राज्यपाल को ज्ञापन दिया था कि वीपी सिंह वित्त मंत्री के रूप में ५ हजार एकड़ जमीन चोरी छिपे रखे हुए हैं और झाड़ों को दिखाकर एक करोड़ रुपए मुआवजा ले लिया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि अपने बेटे की अमरीका के एक बैंक में नौकरी दिलवाकर उस बैंक को भारत में सुविधा दिलायी और दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति बनायी। ये आरोप कांग्रेस ने नहीं, विपक्ष ने वीपी सिंह पर लगाये थे। छह महीने बाद यदि उसी ठग को मसीहा बना दिया जाये, तो आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खुलती?*

माया : भारतीय राजनीति के इतिहास में विपक्षी नेताओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग पहली दफा हो रहा है। क्या ऐसी भाषा में हमला करने में आपकी 'योग्यता' को देखते हुए ही आपको यह पद दिया गया है, जबकि पहले से ही दो मंत्री इस विभाग में कार्यरत थे?

तिवारी : *विपक्ष पर हमला कौन करता है? हेगड़े नंगा पकड़ा गया। यह हमारा किया है या जनता पार्टी वालों का? जब जनता पार्टी टूट रही थी, तो हेगड़े अपने दोस्तों और जानी-अनजानी महिलाओं का टेलीफोन टेप कर रहा था। इसके अलावा रशीद हत्याकांड पर परदा डालने, जाली मोइले टेप बनवाने और सौ करोड़ की जमीन का घपला करने से भी उसका मुंह काला हुआ। देवीलाल के बेटे अभागे हरियाणा को लूटकर खा रहे हैं। एनटी रामाराव महिलाओं की तरह कानों में बालियां डालकर, नाक में कील डालकर और साड़ी पहनकर इसलिए सोता है कि वह प्रधानमंत्री बन जाये। क्या यह भी कांग्रेस वालों ने किया है? वीपी सिंह कहता है कि हम सत्ता नहीं चाहते। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है भारतीय राजनीति का वह पामेला बोर्डेस है। क्या यही आदमी नयी व्यवस्था देगा इस देश को वह भी विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू जैसों*

के साथ मिलकर? अरुण नेहरू जब हमारे दल में था, तो सभ्यता के लंबे इतिहास में सबसे भ्रष्ट, गिरा हुआ माना जाता था। यदि देवीलाल जैसे लुटेरों, हेगड़े जैसे ठगों का हम परदाफाश करते हैं, तो क्यों सवाल उठाया जाता है? मेरी भूमिका एक देशभक्त और समर्पित राजनीतिक की है जो मंत्री रहूं या न रहूं बराबर जारी रहेगी। जिन दिनों ज्ञानी जैल सिंह एक झटके में जनतंत्र, गणतंत्र और संविधान की हत्या करने और राजीव गांधी से दो-दो हाथ करने के लिए उतारू थे, उन्हीं दिनों विपक्ष, गोयनका प्रेस, देशद्रोही और तस्करों के नेता जेठमलानी ने राजीव गांधी के चरित्रहनन का अभियान चलाया था। आरएसएस का आदमी अरुण शौरी जो छद्मवेषी पत्रकार है, भाड़े का टट्टू है, झूठ की गंगा बहा रहा था। हम (मेरा मंत्रालय) गोयनका प्रेस के विपरीत जवाबदेह हैं। जहां तक सूचना प्रसारण मंत्रालय में दो मंत्रियों के अलावा मेरी नियुक्ति का सवाल है, वह इतने बड़े व महत्वपूर्ण विभाग को देखते हुए अनुचित नहीं।

माया: *क्या इसी के लिए मीडिया को रौंदा जा रहा है?*

तिवारी: *यह गलतफहमी है। चुनाव-परिणाम सिर्फ रेडियो-टीवी की खबर तय नहीं करते। यदि अखबार में कुछ छपने से कोई चुनाव जीत जाये, तो जितने अखबारी बाघ हैं, वे इस देश के प्रधानमंत्री वर्षों पहले हो गये होते।*

माया: *क्या आपको ये निर्देश नहीं हैं कि येन-केन-प्रकारेण आलोचना पर लगाम लगायी जाये या उसके प्रभाव को कम किया जाये और सरकार की छवि को जा-बेजा तरीके से चार चांद लगाये जायें?*

तिवारी: *जितना कीचड़ आप लोगों ने फेंका है,* उसके बावजूद कांग्रेस की छवि लोगों में बहुत अच्छी है। हमें मीडिया के माध्यम से देश के सामने दरपेश चुनौतियों-विघटनकारी, फिरकापरस्त, जातिवादी, प्रतिक्रियावादी ताकतों का सामना करना है। जनता के ज्वलंत मसलों, देश की एकता, सुरक्षा और विकास के मुद्दों को उजागर करना है। देश के आत्मबल को तोड़ने के लिए हमारे खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा गया है। इसीलिए जनता का आत्मबल बरकरार रखने के लिए देश के चौमुखी विकास और गौरव की जानकारी दूरदर्शन-रेडियो से देना आवश्यक है। इन मुद्दों को पत्र-पत्रिकाएं अनदेखा करती हैं।

माया: आपके अनुसार पत्र-पत्रिकाओं में ये बातें उजागर नहीं होतीं। क्या इसलिए सरकारी मीडिया को सरकारी भोंपू बनाया जा रहा है?

तिवारी: ऐसा नहीं है। सरकारी मीडिया जनता का मीडिया है। इसलिए जनता की समस्याओं, आशा-आकांक्षाओं, देश की समस्याओं, उपलब्धियों और खामियों को इसके माध्यम से उजागर करना आवश्यक है।

माया: सरकारी मीडिया की विश्वसनीयता पर जो प्रश्नचिह्न लग गया है, उसके बारे में आपका क्या मत है?

तिवारी: हमारी ऐसी पार्टी है, जिसके कान जमीन से जुड़े हुए हैं। लोगों के पैरों की आवाज, उसकी सांसों की आवाज, उनके सोच की आवाज आदि को अपने व्यवहार में उतार उसी के अनुसार हम अपनी नीतियां बनाते हैं। यह केवल अरुण शौरी कहता है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता खतम हो गयी। उसके अनुसार तो राजीव सरकार को दो वर्ष पूर्व ही अपदस्थ हो जाना चाहिए था। किंतु हमारी विश्वसनीयता जनता तय करेगी, गोयनका प्रेस नहीं।

हम कोई भगोड़े नहीं,
दलबदलू, प्रपंची, ठग नहीं हैं, जैसा
वीपी सिंह हैं।
प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसने अपनी
आत्मा ही बेच दी है।
विपक्ष का खोखलापन देखिए कि
४० साल से कोई
विकल्प देने की जगह उस आदमी के पास
गया जो कांग्रेस का भगोड़ा है।

माया: सरकारी मीडिया पर आरोप इसलिए लगा है कि उसमें वास्तविकता और पेशागत महारत दोनों को दरकिनार कर दिया गया है।

तिवारी: *जनता दल वाले आज जो आश्वासन दे रहे हैं कि हम सत्तारूढ़ होने पर दूध-घी की नदियां बहायेंगे, दूरदर्शन-रेडियो को स्वायत्तता देंगे, उसकी क्या विश्वसनीयता है? वही विद्याचरण शुक्ल और अरुण नेहरू उसके नेता हैं, जिनकी विपक्ष उस समय, धज्जियां उड़ाता था, जब वे कांग्रेस के मंत्री थे। यही लोग दूरदर्शन-आकाशवाणी केंद्रों पर धरना देने की आज बात करते हैं। स्वायत्तता और वास्तविकता की मांग आप लोग गोयनका से क्यों नहीं करते?*

माया: *मधु लिमये के एक प्रकाशित लेख के दूरदर्शन-आकाशवाणी पर प्रमुखतापूर्वक आधे-अधूरे प्रसारण का आदेश आपने क्यों दिया था?*

तिवारी: *यह सही नहीं। सवाल है खबर के महत्व का। वह पहले एक पत्रिका में छपा। फिर उसके सूचना महत्व को देखते हुए दूरदर्शन-रेडियो ने प्रसारित किया। वह लेख विकल्प का दावा करने वाले जनता दल के ताजा संघर्ष से जुड़ा था, इसलिए उसे जानने में जनता की रुचि थी।*

माया: *क्या उद्देश्य जनता में वीपी सिंह की छवि को बिगाड़ना नहीं था?*

तिवारी: *वीपी सिंह की छवि को उसके अपने लोगों ने क्या बनाया है? उन्होंने स्वयं क्या किया है? जिस भाजपा से वह रोज समझौता कर रहा है, उसी की नेता विजया राजे सिंधिया का बयान अखबार में छपा कि इस आदमी (वीपी सिंह) ने हम लोगों को ठगा। आरएसएस से कहा कि रामजन्मभूमि देंगे और उधर हाजी मस्तान से भी कहा कि तुमको बाबरी मस्जिद देंगे। उसकी (वीपी सिंह) क्या छवि है, यह जनता को मालूम है, भले ही आप लोग कितना ही पाउडर और अन्य सौंदर्य प्रसाधन क्यों न लगायें।*

माया: *जवाहर रोजगार योजना और पंचायत राज के बहाने सुबह-शाम कांग्रेस का अति प्रचार और विपक्ष का दुष्प्रचार क्या मतदाताओं पर उलटा असर नहीं डालेगा?*

तिवारी: *हमारे मतदाता बहुत परिपक्व हैं। वे अति प्रचार अथवा दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होते। जो केवल प्रचार के बल पर जीवित हैं वे ऐसी बात करते हैं। हमारा अपने काम पर विश्वास है।*

माया: *यदि अपने पर इतना विश्वास है, तो वीपी सिंह को निशाना बना विपक्ष के ऊपर इतना अधिक आक्रमण क्यों सरकारी मीडिया कर रहा है?*

तिवारी: *वीपी सिंह तो अर्धपुरुष, पाखंडी, ठग और सिद्धांतहीन है। मैंने उसे कभी चुनौती नहीं माना। वीपी सिंह को आप लोगों ने कागजी बाघ बनाकर विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया है। वह अंतरराष्ट्रीय ताकतों का एक*

मुखौटा मात्र है। हम उन ताकतों को कभी अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि सौ वर्ष से हम उन्हीं ताकतों—साम्राज्यवाद, सामंतवाद और सांप्रदायिकता से जूझ रहे हैं। इन्हीं ताकतों के गठबंधन से लड़ने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ था। यही ताकतें आज फिर एकजुट हैं।

माया: जनता दल और भाजपा के संभावित गठबंधन से क्या आप लोग इसलिए चिंतित हैं कि सीधी टक्कर में कांग्रेस हार जायेगी।

तिवारी: मैं इसे देश की चुनौती मानता हूं। यदि भाजपा जैसी फिरकापरस्त और संकीर्णता से ग्रस्त ताकत सत्तारूढ़ हुई, तो देश का विभाजन नहीं तो और क्या होगा? वीपी सिंह ऐसी अवसरवादी, फिरकापरस्त, विघटनकारी ताकतों का प्रतिरूप बन गया है। ऐसी ताकतों का उभरना ही चिंता का विषय है।

माया: पत्र-पत्रिकाओं का भी तो आपने गला घोंटना शुरू कर दिया है।

तिवारी: यह आरोप बिलकुल निराधार है। जनतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पत्र-पत्रिका पर ऐसा नियंत्रण कोई नहीं कर सकता। जो आज दूरदर्शन और रेडियो की स्वायत्तता और पत्र-पत्रिकाओं की आजादी की मांग करने चले हैं, वे स्वयं अपने शासनवाले राज्यों में पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? देवीलाल जो भी पत्रकार उनके खिलाफ लिखता है उसे जेल भेज देते हैं। यही एनटी रामाराव भी करते हैं। हेगड़े ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में एक दर्जन पत्रकारों के टेलीफोन टेप कराये थे। ये लोग किस मुंह से पत्र-पत्रिकाओं को आजादी देने की बात करते हैं? हां, हम पत्र-पत्रिकाओं के स्वयं के आत्मसंयम में विश्वास करते हैं, जिसकी बेहद जरूरत है।

माया: चिकने (ग्लेज्ड) कागज पर ३० प्रतिशत तट कर बढ़ाना क्या परोक्ष रूप से विचारों पर पाबंदी लगाना नहीं? मात्र १२ करोड़ रुपए की अल्प आय के लिए सरकार ने ऐसा क्यों किया?

तिवारी: पत्र-पत्रिकाओं के छपने से ही विचार व्यक्त नहीं होते। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना अधिक नहीं कि हम भारी मात्रा में चिकने कागजों के आयात के लिए उस पर धन खर्च कर सकें। कुछ पत्रिकाएं ही इसका प्रयोग करती हैं, इसलिए इसमें मूल्यवृद्धि की गयी है। फिर भी जो समिति बनी है, वह इस मुद्दे पर भी विचार करेगी।

माया: सरकारी दबाव का नमूना यह है कि स्टेट्समैन की संपादकीय नीति के दंडस्वरूप उसके भवन-निर्माण में बाधा पहुंचायी गयी और विनोद मेहता जैसे संपादक को मालिकों के व्यावसायिक हितों पर चोट पहुंचने के कारण बाहर जाना पड़ा।

तिवारी: सरकार कभी किसी अखबार पर दबाव नहीं डालती। सतीश शर्मा के नाम पर मनगढ़ंत आरोप उछालने का एक फैशन बन गया है। जहां तक स्टेट्समैन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है कि वह एक बड़ा अखबार नहीं, एक महान संस्थान था, जिसे ईरानी ने मिट्टी में मिला दिया है। वहां कर्मचारियों का ही नहीं, संपादकों का भी भारी शोषण होता है और उन्हें अकारण निकाल दिया जाता है। ईरानी को देश में कोई नहीं जानता, किंतु हर साल वे अमरीका से पत्रकारिता के नाम पर दो-दो पुरस्कार ले आते हैं। उनका सीधा उद्देश्य पत्रकारिता के नाम पर अपना व्यावसायिक हित साधना है। जहां तक विनोद मेहता प्रकरण का सवाल है, उस संबंध में कुलदीप नैयर ने एक मीटिंग बुलायी, जिसमें विनोद मेहता के अलावा वीपी सिंह, इंदर कुमार गुजराल भी शामिल थे। इसमें उन्होंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि वे (विनोद मेहता) सरकार के खिलाफ बोलें और यह कहें

अरुण नेहरू
जब हमारे दल में था,
तो सभ्यता के
लंबे इतिहास में सबसे भ्रष्ट,
गिरा हुआ
माना जाता था। यदि
देवीलाल जैसे लुटेरों, हेगड़े जैसे
ठगों का हम
परदाफाश करते हैं, तो क्यों सवाल
उठाया जाता है?

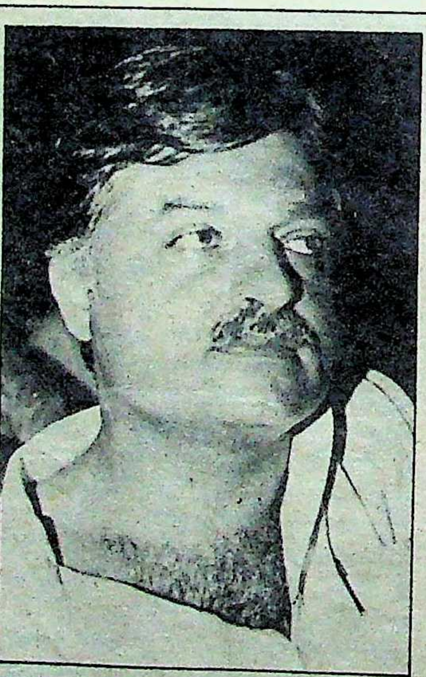

सतीश शर्मा
के नाम पर मनगढंत आरोप
उछालने का एक फैशन बन गया है।
जहां तक
स्टेट्समैन का सवाल है,
सारी दुनिया जानती है कि वह
एक बड़ा अखबार नहीं,
एक महान संस्थान था, जिसे ईरानी ने
मिट्टी में मिला दिया है।

कि प्रेस की स्वतंत्रता को सरकार से खतरा है। किंतु श्री मेहता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कदाचित वे जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को सरकार से नहीं, सेठों से खतरा है।

माया: सरकार प्रेस को प्रतिद्वंद्वी के रूप में क्यों देखने लगी है?

तिवारी: राजनीतिक पार्टियां कट्टरपंथी हो सकती हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ होता है, किंतु अखबार का काम सत्ता की राजनीति में पड़ना नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं, तो किसी-न-किसी पार्टी के पक्षधर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र-पत्रिकाओं की स्वतंत्र-निर्णायक भूमिका जनता के बीच समाप्त हो जाती है। पत्रकार को अम्पायर की भूमिका निभानी चाहिए। जिसकी गलती हो, उसकी आलोचना-समीक्षा कर सलाह दें। दुर्भाग्य से देश में जो गोयनका संस्कृति इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से चल रही है, वह तो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों-चालबाजियों का एक हिस्सा है। उन पर (गोयनका) कुछ आर्थिक अपराधों के मुकदमें चल रहे हैं, इसलिए वे अखबार की आजादी का हल्ला मचा रहे हैं। गोयनका, अरुण शौरी, हर्शमैन और ज्ञानी जैल सिंह प्रकरण के माध्यम से जनतंत्र और गणतंत्र की हत्या का षड्यंत्र भी कर चुके हैं। शौरी ने प्रथम पृष्ठ पर लेख लिखा कि 'अब इस सरकार को बर्खास्त करने का समय आ गया है।' प्रेस की यह भूमिका नहीं है। गोयनका के दिमाग में यह बात आ गयी है कि वे सरकार बना-बिगाड़ सकते हैं।

> गोयनका देश का
> सबसे बड़ा कर-चोर है।
> अरुण शौरी
> आरएसएस का घुसपैठिया
> और दुमछल्ला है।
> उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात
> बहुत हास्यास्पद लगती है।
> भ्रष्टाचार की दुहाई देनेवाला शौरी
> दशकों से जारी गोयनका के
> भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर कोई
> लेख क्यों नहीं लिखता?

माया: क्या गोयनका, शौरी से सरकार इसलिए नाराज है, क्योंकि वे लगातार सरकारी भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था का भंडाफोड़ करते रहे हैं?

तिवारी: गोयनका देश का सबसे बड़ा कर चोर है। अरुण शौरी आरएसएस का घुसपैठिया और दुमछल्ला है। उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात बहुत हास्यास्पद लगती है। भ्रष्टाचार की दुहाई देनेवाला शौरी दशकों से जारी गोयनका के भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर कोई लेख क्यों नहीं लिखता?

माया: जनता दल ने दूरदर्शन-रेडियो को स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही है। क्या यह अनुकरणीय कदम नहीं?

तिवारी: जनता दल झूठे प्रचार, छद्म गुहार अनरगल धोखेबाजी का काम कर रहा है। विद्याचरण शुक्ल जिनके सूचना मंत्रालय के मंत्री-पद की कार्रवाइयों पर दो-चार सौ ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, इनकी सेना के सेनापतियों मे हैं।

माया: किंतु वे श्रीमती गांधी के आदेशों का ही तो पालन कर रहे थे।

तिवारी: यदि कोई आदमी कांग्रेस सरकार का मंत्री रहे, तो देश का सबसे बड़ा फासिस्ट और चोर है। जब कांग्रेस से निकल जाये, जैसा कि वीपी सिंह—जोकि सबसे बड़ा ढोंगी, चोर और सामंत है—तो वह सबसे सच्चा, ईमानदार और जनहितैषी बन जाता है। इसके अलावा जिस आडवाणी (भाजपा) से साठगांठ, साजिश और समझौता हो रहा है, वह सिद्धांत-व्यवहार में पूरा फासिस्ट है। ७७ से लेकर ७९ तक आडवाणी युग में दूरदर्शन रेडियो के काले काल में जनता पार्टी के ही अन्य घटकों के बारे में एक लाइन भी नहीं प्रसारित होता था। हम १९७७ में चुनाव हारे थे, युद्ध नहीं। किंतु इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय नेता थीं, उनके साथ युद्ध बंदी जैसा व्यवहार किया गया था। रेडियो-दूरदर्शन से उनके खिलाफ रातदिन जहर उगला जाता था। कहां गया था जनता पार्टी का १९७७ का वह चुनाव घोषणा पत्र, जिसमें संचार माध्यमों की स्वायत्तता का वायदा किया गया था? फिर आप लोगों की आंख में धूल झोंकने आ गये हैं। हमारी समझ से हमारी रेडियो-दूरदर्शन की स्वायत्तता इस अर्थ में है कि हम संसद द्वारा सुनिश्चित दिशानिर्देश से काम करते हैं। हमारी हर गतिविधि पर संसद में बहस और मूल्यांकन होता है।

माया: सुना है फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा न केवल आपके खिलाफ खड़े होने का, बल्कि आपको पराजित करने का दावा कर रहे हैं।

तिवारी: शत्रुघ्न सिन्हा उसी विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिसका मैं शिक्षक था। इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चाहे कोई भी हो मैं चुनाव विश्वास से लड़ूंगा। मेरी तो चुनौती बड़े से बड़े विपक्षी नेता को है।

माया: बावजूद इसके कि आपके मंत्रालय में ही आपके विरोधियों की कमी नहीं, क्योंकि आपने सबको हाशिये पर डाल दिया है।

तिवारी: यह महज अफवाह है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा यह धारणा फैलायी जा रही है। श्री भगत विभाग के प्रमुख मंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार है। मैं राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूं। किसी को हाशिये पर डालने का प्रश्न नहीं। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं।

—रंजना कक्कड़

कानपुर पर विशेष

औद्योगिक मानचित्र पर कानपुर

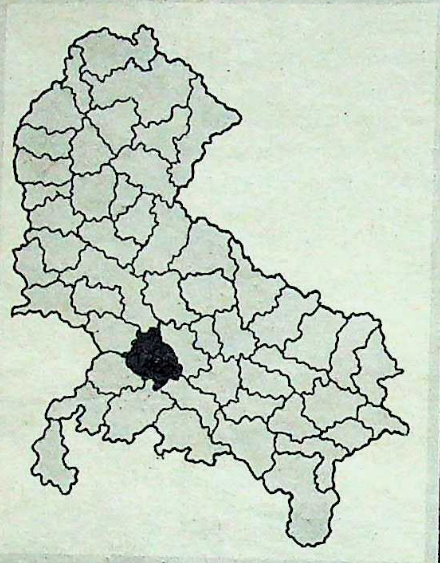

यह विडंबना ही है कि १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम और उसके बाद चली आजादी की लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभानेवाला और आजाद भारत की केंद्र सरकार का नियंता उत्तर प्रदेश आजादी के ४२ सालों बाद भी आज विपन्न है। यह देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन दो-तिहाई से अधिक आबादी गरीब है। इस प्रदेश के सिर्फ २७.१६ प्रतिशत लोग ही पढ़ना-लिखना जानते हैं। जहां पूरे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय ३१८४ रुपए (१९८७-८८ की कीमतों के अनुसार) है, वहीं उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की सालाना औसत आय २४८८ रुपए है। उत्तर प्रदेश की इस विपन्न अवस्था का मुख्य कारण है, इस प्रदेश की अनेक आधारभूत मामलों में घोर उपेक्षा। देश की कुल आबादी (८० करोड़) का सवा सोलह प्रतिशत (१३ करोड़) उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लेकिन देश की कुल जमीन का सिर्फ ८.९५ प्रतिशत क्षेत्र ही उसके हिस्से में आया है। प्रदेश के आर्थिक विकास में केंद्र की हिस्सेदारी सिर्फ पांच प्रतिशत है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर को जहां क्रमश: प्रतिव्यक्ति ३७९.७५, ३६०.८२, ५३०.६१, ६६५.७१ और ६२५ रुपए की योजनाएं दीं, वहीं उत्तर प्रदेश को सिर्फ प्रतिव्यक्ति १९४.०४ रुपए मिले। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन त्वरित आर्थिक विकास के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू औद्योगीकरण को आधारभूत माध्यम मानते थे, लेकिन आजादी के ४२ वर्षों बाद भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन का आलम यह है कि यहां के ५८ जिलों में से ११ जिले ऐसे हैं, जहां एक भी उद्योग नहीं है। ८५७ में से ७० विकास खंड उद्योगशून्य हैं।

उद्योग आयुक्त देवीदयाल का दावा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के खतम होने तक (१९८५) जहां ३५७५ करोड़ रुपए से ६९० बड़े और मझोले तथा ११०७१० लघु इकाइयों की स्थापना हुई थी, वहीं सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में (३१ मार्च, १९८९ तक) १९४ बड़े व मझोले एवं ८५५११ लघु उद्योगों व ११६२४८ दस्तकारी इकाइयों को मिलाकर कुल २०१९५३ इकाइयां लगायी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अपनी स्थापना (१९६१) से अब तक ४७ जिलों में करीब ३५ हजार एकड़ जमीन हासिल करके ११२ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर चुका है। इसमें से लगभग १९ हजार एकड़ जमीन विकसित करके उद्यमियों को दी जा चुकी है। अगले तीन सालों के अंदर ३० नये औद्योगिक क्षेत्र तैयार

When it comes to spinning yarn we have the last word

Yes, we spin yarn. And spin very well. In fact, they say we are almost the last word in producing quality yarn for the non-organised sector of textile industry - the handloom and powerloom weavers. U. P. State Textile Corporation Ltd. U. P. State Spinning Mills Company (No. 1) Ltd. U. P. State Spinning Mills Company (No. 2) Ltd. and U. P. Co-operative Spinning Mills Federation Ltd. are pioneers in cotton spinning in the public / cooperative sector. Whatever the requirement of the weavers in the count range of 6s to 80s cotton yarn, our mills are ever ready to meet it. Quality is our watch ward All our professional expertise is devoted to maintaining the highest standards of quality in conformity with user's needs. Our excellent service and streamlined delivery schedule keep every thing running smoothly. And our prices are the most competitive. Having established ourselves as yarn market leaders in Northern India, we are poised for a major break-through in the international yarn market. Our yarn has already reached the markets of U. K., Sri Lanka, Kuwait, Yugoslavakia, Bangladesh, Italy, Belgium, West Germany, Vietnam, U. S. A. etc.

We are the yarn professionals
UPSTC
UPSSM
UPCSMF

KRISHNA

U. P. STATE TEXTILE CORPORATION MILLS Jhansi, Kashipur, Sandila, Meerut, Jaspur.
Subsidiary Companies
1. U. P. STATE SPINNING MILLS CO. (NO. I) LTD. MILLS Rae Bareili, Akbarpur, Barabanki, Maunath Bhanjan.
2. U. P. STATE SPINNING MILLS CO. (NO. II) LTD. MILLS Meja (Allahabad), Bando Jaunpur & Ballia.
3. BHADOHI WOOLLENS LIMITED, BHADOHI [VARANASI].
U.P. CO-OPERATIVE SPINNING MILLS FEDERATION LTD. MILLS
Baheri (Bareilly), Kampil (Farrukhabad), Mausima (Allahabad), Fatehpur, Amroha (Moradabad) Bahadurganj (Ghazipur), Bulandshahr, Etawah, Nagina (Bijnore), Maghar (Basti) and Mahmoodabad (Sitapur)

कानपुर में सर्वप्रथम

	सन
● ईस्ट इंडिया कंपनी की एजेंसी	१७७८
● कानपुर अस्तित्व में	१८०३
● कानपुर से होती हुई ग्रांड ट्रंक रोड का इलाहाबाद से दिल्ली तक का निर्माण	१८३३
● गंगा में सरकारी नावों के पुल का निर्माण	१८३३
● नवाबगंज में कंपनी बाग का निर्माण	१८४७
● गंगा नहर की शुरुआत	१८५४
● कानपुर-इलाहाबाद के बीच ईस्ट इंडिया रेल	१८५९
● पहली मिल एलंगिन काटन एण्ड स्पिनिंग कं० लि०	१८६१
● बैंक आफ बंगाल की कानपुर शाखा	१८६३
● कूपर गंज का निर्माण	१८६६
● संभवतः प्रथम छापा खाना 'शोल एलूर प्रेस'	१८७५
● कानपुर का निर्यात ३४ लाख रु०, आयात ५० लाख रु०	१८७५
● गंगा पर लोहे के पुल का निर्माण	१८७५
● कानपुर ऊलेन मिल्स (लाल इमली)	१८७६
● कलेक्टरगंज गल्ला मंडी का उद्‌घाटन	१८७९
● कूपर गंज में टाउन हाल (वर्तमान चाचा नेहरू अस्पताल) का निर्माण	१८७९
● कूपर एलेन कंपनी (वर्तमान टेफको)	१८८०
● जूट मिल 'नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज जूट मिल्स'	१८८३
● अपर इंडिया चेम्बर्स आफ कामर्स	१८८८
● फूलबाग की स्थापना	१८९०
● बरफ फैक्ट्री 'जान्स आइस फैक्ट्री'	१८९६
● इंडिया रोलिंग मिल	१९०४
● बिजली का आगमन	१९०६
● गवर्नमेंट स्कूल आफ डाइंग एण्ड प्रिंटिंग (वर्तमान सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट)	१९१४
● यूपी चेम्बर आफ कामर्स	१९१४
● शक्कर कमेटी (वर्तमान शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन)	१९१९
● कपड़ा कमेटी	१९२५
● मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ यूपी	१९३२
● वनस्पति कारखाना 'गणेश फ्लोर मिल्स'	१९३४
● नार्दर्न इंडिया एम्प्लायर्स एसोसियेशन	१९३७
● शीत गृह 'अपर इंडिया कोल्ड स्टोरेज'	१९४९

करने के उद्येश्य से १२ हजार एकड़ जमीन हासिल करने की योजना है। निगम के प्रबंध निदेशक ललित श्रीवास्तव के अनुसार "निगम विभिन्न क्षेत्रों में १८ परियोजनाएं चला रहा है।" लेकिन ३० हजार इकाइयों में ५४० करोड़ की पूंजी लगानेवाले उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक आरएन त्रिवेदी बताते हैं, "इनमें से ३५-४० प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां नकारा होकर बीमार इकाइयों की सूची में शामिल हो चुकी है।" इन सबके बावजूद प्रदेश का सकल वार्षिक औद्योगिक उत्पादन ११ हजार करोड़ रुपए है जो प्रदेश की कुल आय (३१६३६ करोड़ रुपए) का करीब एक तिहाई है। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न, वनस्पति तेल और चीनी का उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पादन का क्रमशः २१, १८ और ३० प्रतिशत है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सीमेंट का ३.१ प्रतिशत, सूती कपड़े का ५.५ प्रतिशत, सूत का ८.१ प्रतिशत

IDEAL TV

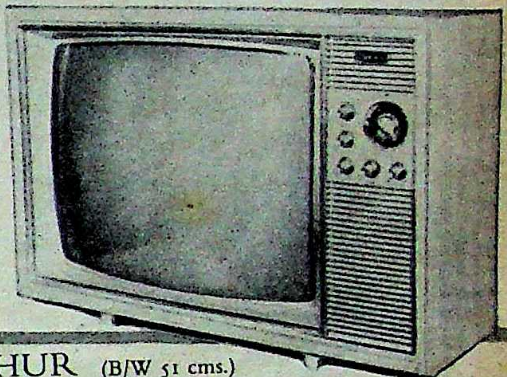

MADHUR (B/W 51 cms.)

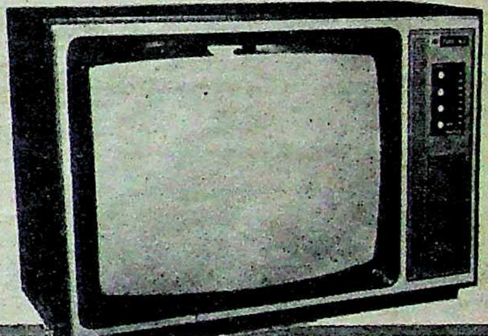

CT O77 (COLOUR TV)

Publisites

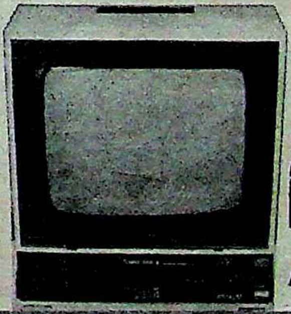

A Govt. of India Enterprise

IDEAL TV
An Ideal Choice

COREX–202 At
36 cms. PORTABLE

Manufacturers:
RAJU ENGINEERS
107/234-B, Nehru Nagar, Kanpur-208 012. Phone—241284, 247284
Factory: C 1 & 2, Industrial Estate, Bindki Road, Fatehpur. Phone: 34
Dealership Enquiries Solicited.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल

उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन यहां के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए परिव्यय का प्रतिशत मात्र छह है। इससे भी रोचक तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निगम एवं उपक्रम प्रतिदिन एक करोड़ ८५ लाख रुपए का घाटा दे रहे हैं। इन विसंगतियों से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं और इनकी स्थापना और परिवर्धन का कार्य भी हो रहा है लेकिन संपूर्ण कार्य योजना असंतुलित है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण खुद कानपुर है, जिसे अंग्रेज हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा करते थे और जिसकी गणना प्रदेश के आठ प्रमुख औद्योगिक नगरों में होती थी, लेकिन आज वही कानपुर बीमार औद्योगिक इकाइयों का जखीरा बन चुका है, तथा असंतुलित नगर विस्तार और आबादी के बढ़ते बोझ से यह शहर चरमरा रहा है।

कानपुर का औद्योगिक परिदृश्य

कानपुर को अति प्राचीन नगर साबित करने के लिए विद्वान कानपुर का संबंध महाभारत काल के भगवान कृष्ण से अथवा दानवीर कर्ण से जोड़ते हैं, लेकिन कानपुर का 'कान्हापुर' नाम से सर्वप्रथम उल्लेख मुगल सम्राट अकबर के समय में अब्बास शेरवानी द्वारा लिखित 'तारीखे शारशाही' में हुआ, तथापि वर्तमान कानपुर शहर अवध की दीवानी अंग्रेजों को मिलने के बाद सन १८०३ में पहली बार अस्तित्व में आया। १८३३ में यहां गंगा पर पहला नावों का पुल बना, लेकिन कानपुर के उद्योग नगरी के रूप में विकसित होने की कहानी १८५७ के विप्लव के बाद से शुरू होती है। १८५७ के विप्लव के कारण लखनऊ के अनेक रईस कानपुर आकर बस गये। १८५९ में कानपुर में रेल आयी। कानपुर के औद्योगिक उत्थान में इन दोनों ही घटनाओं की प्रमुख भूमिका रही है। २२ नवंबर, १८६१ को यहां पहली बार म्यूनिसिपल कमेटी का गठन हुआ और इसी वर्ष यहां एलगिन काटन ऐंड स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड ने पहली सूती मिल लगायी। १८७५ में यहां गंगा पर लोहे का पुल बना और उसके बाद यहां धड़ाधड़ कारखाने स्थापित होने लगे। हार्नेस और कूपर एलेन कंपनियों ने चमड़े के कारखाने लगाये और कानपुर ऊलेन मिल्स (१८७६) की स्थापना हुई। यहा पहली जूट मिल 'नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज जूट मिल्स' १८८३ में और बर्फ फैक्ट्री 'जान्स आइस फैक्ट्री' १८९६ में स्थापित हुई। इस प्रकार कानपुर का प्रारंभिक औद्योगिक विकास १८६० से १९२० के बीच हुआ। इस दौरान कोई खास बड़े उद्योग तो नहीं लगे, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध में उद्योगों ने यहां अच्छी खासी कमाई की थी।

श्री प्रदीप भटनागर

कानपुर में बीआईसी ग्रुप की घाटे में चल रही सात कपड़ा मिलों के उत्पादन को ६० करोड़ से बढ़ाकर १८० करोड़ रुपए करके कंपनी को साढ़े तीन करोड़ रुपए का मुनाफा दिलानेवाले डीएन दीक्षित आजादी के बाद के ३३

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

प्रदान करता है :

- योजनाओ के स्थापना तथा समीकरण हेतु सहायता,
- 60 लाख रु. तक कम्पनियों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों को व रु. 30 लाख प्रोप्राइटर शिप। पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म को सावधि ऋण
- रिकप। शेड्यूल्ड बैंक के सहयोग योजना को अधिकतम पूंजी रु 3.00 करोड़ तक की वित्तीय सहायता क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग के लिए पुनः स्थापना सहित उद्योग के नवीनीकरण मशीनरी एवं संयत्र के पुनरुद्धार या संतुलन आदि के लिए सावधि ऋण
- महत्वाकांक्षी डाक्टरों को नर्सिंग होम खोलने हेतु नवीनतम इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरण क्रय करने हेतु सावधि ऋण
- सेम्फक्स स्कीम के अन्तर्गत भू. पू. सैनिकों (भू. पू. सैनिको की विधवाओं तथा विकलांग कर्मियों समेत) को अधिकतम रु. 9.00 लाख की वित्तीय सहायता
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की इक्विपमेण्ट

रिफइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत ऋण

- महिला उद्यमियो द्वारा प्रोत्साहित। संचालित सभी लघु इकाइयो कुटीर ग्रामीण एव अति लघु इकाइयों को

वित्तीय सहायता

- सभी एस. एस. आई. इकाइयो को क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आर. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत बीमार इकाइयों के पुर्नजिवीकरण हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता
- एशियाई विकास बैक की लाइन आफ क्रेडिट के रुपयों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा ऋण रूप मे लघु व मध्यम उद्योगो की सहायता
- विशेष रूप से लघु स्तरीय क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग अन्य जिलों में तथा पिछड़े क्षेत्रो मे उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता
- निर्यातक इकाइयों के शत प्रतिशत निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सहायता।

विशेष सहायता

अधिकतम रु 5.00 लाख की वित्तीय सहायता योजना की नियत पूंजी हेतु तथा रु. 2.50 लाख कार्यशील पूंजी अति लघु व लघु इकाइयां जहां परियोजना की लागत रु. 5.00 लाख (सिंगल बिन्डो स्कीम के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी घटकों को छोड़कर) से कम हो

निगम के कार्यालय :-

प्रधान कार्यालय : 44/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

क्षेत्रीय कार्यालय : इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बुलन्दशहर, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हल्द्वानी, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोयडा, सहारनपुर, वाराणसी।

KRISHNA

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
उद्यम एवं उद्यमियों की सहायता के लिए

यूपिका
हैन्डलूम्स

UPICA

- सिल्कन, बनारसी व चिकन साड़ियाँ
- सिल्कन, कॉटन बेडशीट व बेड कवर्स
- टैपेस्ट्री, व परदे का कपड़ा
- ड्रैस मैटीरियल सिल्कन व कॉटन
- टेरीकाट सूटिंग व शर्टिंग
- मुलायम तौलिए, पिलो कवर्स टी.वी. कवर्स
- मनमोहक मखमली रजाइयां

35% की भारी छूट

यू. पी. इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एशोसियेशन लि.
यूपिका भवन सर्वोदय नगर, कानपुर

''यूपिका'' के सभी शो रूमों में उपलब्ध

THINK

श्री डी०सी० [illegible]

श्री यज्ञदत्त मिश्र

सालों को कानपुर के उद्योगों का पतनकाल मानते हैं।

दरअसल, कानपुर के औद्योगिक विकास के लिए १९८० के बाद ही कुछ ठोस कार्य हुए। भारत सरकार की नयी औद्योगिक नीति के अनुसार जिला उद्योग केंद्र योजना, कानपुर मे १ मई, १९७८ से लागू की गयी। इसके पूर्व ९ जून, १९७६ को कानपुर नगर की समस्याओं और देहाती इलाकों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर जनपद कानपुर पहली बार कानपुर नगर तथा कानपुर देहात इन दो जिलों में विभक्त किया गया था, लेकिन एक साल बाद ही १२ जुलाई, १९७७ को इसे पुनः एक जनपद बना दिया गया। कानपुर में जिला उद्योग केंद्र के सक्रिय होने पर कानपुर को विकास की दृष्टि से पुनः देहात और नगर दो जिलों में विभक्त करने की जरूरत महसूस की गयी और २३ अप्रैल, १९८१ को यह जनपद कानपुर नगर (क्षेत्रफल-१०४० वर्ग किमी, जनसंख्या-१९.५१ लाख) और कानपुर देहात (क्षेत्रफल-५१३६ वर्ग किमी, जनसंख्या-१७.९० लाख) इन दो जिलों में बंट गया। इस समय कानपुर शहर में कपड़ा, सूत, ऊनी वस्त्र, जूट, रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, लौह, कृत्रिम अंग और रक्षा सामग्री से संबंधित सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की वृहद और मध्यम श्रेणी की ७५ इकाइयां कार्यरत हैं। ३५ लाख से कम पूंजीवाले २८१६ कारखाने जिला उद्योग केंद्र में १९८५ से अभी तक पंजीकृत हुए हैं। नये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानपुर के उद्यमों को उद्योग विभाग उत्पादित वस्तु के बिक्री कर में पांच वर्ष तक की छूट देता है। जिस उद्योग की प्लांट एवं मशीनरी, भूमि एवं भवन तथा कार्यशील पूंजी तीन लाख से कम है, उसे बिक्री कर में दो वर्ष की छूट दी जाती है। इस समय जिला उद्योग केंद्र प्रदेशव्यापी नीतियों के अनुसार ही लक्ष्यबद्ध योजनाएं बना रहा है और अभी से तय कर लिया गया है कि कहां-कहां किसी क्षेत्र से संबंधित कितने उद्योग लगाने हैं। पूरे प्रदेश के समान ही कानपुर के नगर एवं देहात जनपदों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के द्वारा सरकार इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए तत्पर है।

समस्याएं : सरकारी अधिकारियों के दावों पर गौर किया जाये, तो ऐसा लगता है कि वे बड़ी जल्दी उत्तर प्रदेश को 'देश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश' बना देंगे। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों की नजर में उत्तर प्रदेश और खासकर कानपुर का औद्योगिक परिदृश्य उतना सुहावना नहीं है, जितना कि सरकार द्वारा उसका खाका खींचा जाता है।

सूती मिलें : सात दशक पहले सन १९२१ में कानपुर में जेके काटन मिल से अपने उद्योग की शुरुआत करनेवाले और आज सूती उद्योग में देश के चौथे सबसे बड़े औद्योगिक घराने 'जेके आर्गानाइजेशन' के उत्तरी क्षेत्र के अगुवा डा० गौर हरि सिंघानियां प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की मौजूदा नीतियों और विशेषकर लचर कार्य प्रक्रिया को सुधारने की सख्त जरूरत महसूस करते हैं। वे कागजों पर बनी नीतियों व घोषणाओं तथा उनके अमल के बीच मौजूद खाई को

यू.पी. हैण्डलूम्स

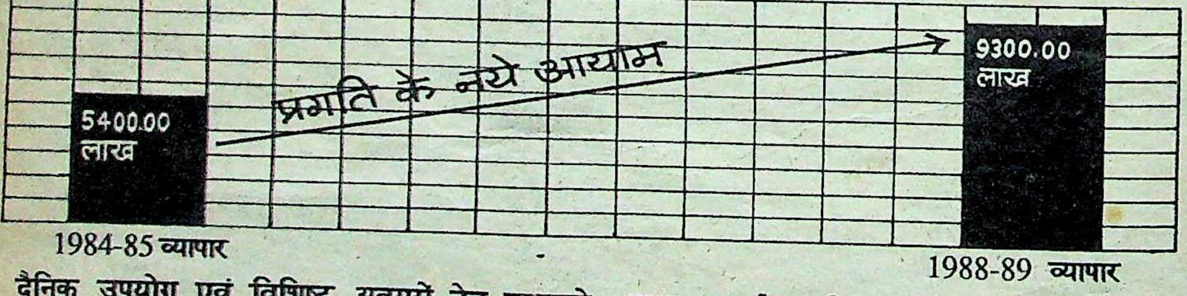

दैनिक उपयोग एवं विशिष्ट अवसरों हेतु लुभावने तथा आकर्षक परिधान-गृह सज्जा के लिए उत्कृष्ट वस्त्रों का संग्रह लेकर यू. पी. हैण्डलूम्स के निम्न विक्रय केन्द्रों में आपका स्वागत है:-

- नई दिल्ली
  अरबिन्दो प्लेस, हौजखास
- बम्बई
  कोलवा सम्मुख रीगल सिनेमा
- बंगलौर
  महावीर शापिंग काम्पलेक्स, के. जी. रो
- मद्रास
  ८७, अन्नासलाई माउन्ट रोड
- कलकत्ता १, लिण्डसे स्ट्रीट
- हैदराबाद
  मयूर कौशल शापिंग काम्प्लेक्स, आबिद रोड
- रौंची मेन रोड
- जयपुर
  १२, जयंती बाजार, एम. आई. रोड
- लखनऊ
  मैफेयर बिल्डिंग, हजरतगंज
- कानपुर
  पी. पी. एन मार्केट
- वाराणसी
  होटल इन्टरनेशनल लहुराबीर
- आगरा
  संजय प्लेस काम्पलेक्स
- गोरखपुर गोलघर
- सहारनपुर
  शहीदगंज, मार्केट
- चण्डीगढ़ सेक्टर-१७

तथा देश भर में फैले १५० अन्य विक्रय केन्द्र निर्यात जानकारी हेतु कृपया सम्पर्क करे :-प्रवन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम
(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)
हथकरघा भवन, जी. टी. रोड, कानपुर (उ. प्र.)

KRISHNA

स्वादिष्ट चटपटे मज़ेदार...
नवरंग®
मिर्च
का अचार
तेल में
PIECES OF CHILLIES, SALT, CHILLIES, MUSTARD, FENUGREEK, EDIBLE OIL, ANISEED, TURMERIC, ASAFOETIDA.

यद्यपि अचार तो बहुत सी कम्पनियों द्वारा बनाये जाते हैं किन्तु नवरंग अचार की विशेष किस्म और अद्भुत स्वाद उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। क्योंकि नवरंग अचार शुद्ध एगमार्क सरसों के तेल एवं एगमार्क अशोक मसाले से तैयार किये जाते हैं। इसलिए क्वालिटी व स्वाद के दावे को सिद्ध करने के लिए एक बार चख कर तो देखें।
क्यों? है न इसका मजेदार स्वाद।

नवरंग
अचार
शीशी एक अचार अनेक

पैकिंग : ५ कि०, २ कि०, १ कि०, ५०० ग्रा० व २५० ग्रा०

मुख्य वितरक
अशोक सेल्स कारपोरेशन
५१/५३, नयागंज, कानपुर-२०८००१

उत्तर प्रदेश के बाहर वितरक/स्टाकिस्ट बनने हेतु सम्पर्क करें

Publisites/NA/B/W/1

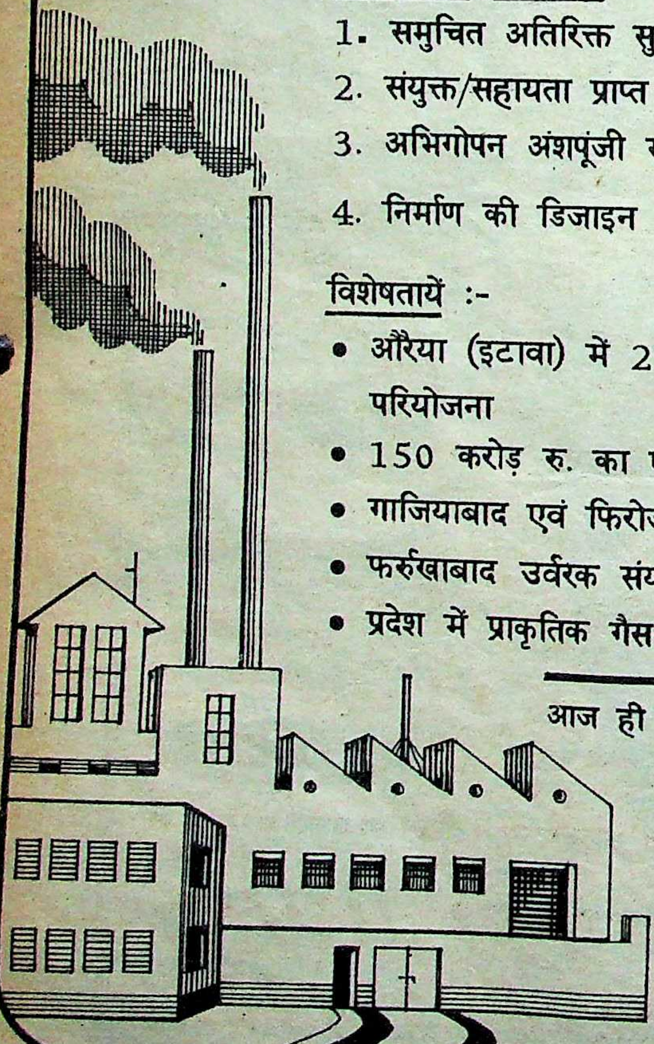

उद्यमियों

upsidc

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम परियोजनाओं के प्रारम्भिक चिन्तन से स्थापित होने तक का सहायक

निगम के मुख्य कार्य :

1. समुचित अतिरिक्त सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
2. संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्रों में परियोजनाओं का प्रवर्तन
3. अभिगोपन अंशपूंजी सहयोग एवं सेतु ऋण द्वारा वित्तीय सहायता
4. निर्माण की डिजाइन व मानचित्र बनाने हेतु परामर्श तथा क्रियान्वयन

विशेषतायें :-

- औरैया (इटावा) में 2000 करोड़ की गैस क्रेकर एवं पेट्रोलियम परियोजना
- 150 करोड़ रु. का एक्रेलिक फाइबर परियोजना
- गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद में प्राकृतिक गैस वितरण परियोजना
- फर्रुखाबाद उर्वरक संयन्त्र
- प्रदेश में प्राकृतिक गैस के समुचित उपयोग की एकीकृत एजेन्सी

आज ही सम्पर्क करें :-

प्रबन्ध निदेशक,
उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.,
117/130, सर्वोदय नगर,
कानपुर-208 005
फोन : 218161-65 पी. बी. एक्स
टेलेक्स : एस. आई. डी. सी. इन. 371

डा० गौरहरि सिंहानिया

औद्योगिक विकास में बाधक मानते हैं। उनकी राय है, "उद्योग से संबंधित कायदे-कानूनों को जब तक सरल और उदार नहीं किया जाता, तब तक महज शोर मचाने से विकास की गति को तेज करना बहुत मुश्किल है।

बीआईसी औद्योगिक समूह के डीएन दीक्षित का कहना है, "सन् सैंतालीस के बाद कानपुर में ऐसा कुछ नहीं था, जिसके दम पर यहां उद्योग पनपते और नयी इकाइयां खड़ी होतीं। दस बड़ी कपड़ा मिलों में दो बंद हो चुकी हैं। बीआईसी को छोड़कर आज भी सारी-की-सारी घाटे में सराबोर है।" वे जोर देकर कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानपुर की सूती मिलें सरकारी अनुदान पर चल रही हैं और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं। तीन सौ करोड़ रुपए सालाना से अधिक का कारोबार करनेवाले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के चेयर मैन सुमन कुमार माडवल बुनकरों को परेशानी से बचाने के लिए हर तीसरे महीने सूत के भाव संशोधित करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के पक्षधर हैं।

अशोक मसाले : कानपुर के नाम को न केवल भारत के कोने-कोने तक पहुंचाने में 'अशोक मसालों' की अहम भूमिका रही है, बल्कि आज अमरीका और सऊदी अरब में भी इसने अपनी धाक जमा ली है। १९५७ में बड़े छोटे स्तर पर इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इस कंपनी के मालिक किशोरी लाल गुप्त ने इस व्यवसाय को मिशन के रूप में स्वीकार किया है। अव्वल दर्जे के कच्चे माल का प्रयोग करने का ही यह नतीजा है कि अशोक मसालों ने मसालों की बड़ी कंपनियों को मात दे दी है।

श्री गुप्ता पैकिंग लागत में जबरदस्त वृद्धि के लिए सरकार की मौजूदा कागज नीति को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि मसालों पर पचास से सौ प्रतिशत तक पैकिंग खर्च आता है। लेकिन मसालों की ताजगी को लम्बे समय तक बरकरार रखना और ग्राहकों की बदलती रुचि के अनुसार अच्छी पैकिंग करना भी जरूरी है।"

होजरी उद्योग : लेकिन उत्तर प्रदेश के होजरी उद्योग में लगे उद्यमी सरकार के बिक्री कर ढांचे से असंतुष्ट हैं। उप्र० होजरी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम नरूला का कहना है, "सरकार ने दोहरी नीति लागू की है। एक ओर तो वह प्रचार माध्यमों के जरिए नये उद्योगों को बिक्री कर से मुक्त रखने की घोषणा करती है, वहीं बिक्री कर विभाग के नुमाइंदे एक-न-एक नुक्ता निकालकर अड़चनें पैदा कर देते हैं। बिक्री कर राजस्व बढ़ाने में ही इनकी दिलचस्पी रहती है। इस विभाग ने सलाहकार समिति तो गठित कर रखी है, लेकिन उनकी न तो कोई भूमिका है और न ही वे उपयोगी सिद्ध हो पा रहे हैं। अफसरान केवल बैठकें करके औपचारिकता पूरी कर लेते हैं।"

श्री डी०एन० दीक्षित

श्री नरूला बताते हैं, "होजरी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश है, परंतु यहां पर होजरी यार्न और होजरी पर अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिक्री कर की मार है और इसी वजह से दूसरे उत्पादक राज्य यहां पर हावी होते जा रहे हैं। तिरुपुर, दिल्ली, कलकत्ता और लुधियाना की होजरी यहां के उत्पादनों पर भारी

रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी

१.सिंचाई हेतु समुचित जल का प्रयोग करें। अधिक जल के प्रयोग से सिंचाई जल की हानि, भूमि की उत्पादकता में ह्रास, भूमि में लवणीयता/क्षारीयता का प्रभाव एवं जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है।
२.रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास कार्यों के अन्तर्गत निर्मित कच्ची, पक्की नालियां, जल निकास नालियां, जल नियंत्रण संरचनायें एवं चकरोड आदि सभी चक सभाओं की सम्पत्ति है, जिनका ठीक प्रकार से रखरखाव सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा करना आवश्यक है।
३.भरपूर पैदावार के लिए समय से सिंचाई, उन्नतिशील बीज, संस्तुत उर्वरक, एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।
४.कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अपनाकर अधिक समृद्धिशाली बनें।

कृषकों को देय सुविधायें

अ. ५-८ हैक्टेयर के खण्ड तक पक्की, कच्ची गूल एवं संरचनाओं के निर्माण पर समस्त लाभार्थियों को शत प्रतिशत अनुदान।
ब. ५-८ हैक्टेयर के खण्ड के अन्तर्गत पक्की, कच्ची गूल एवं संरचनाओं के निर्माण पर समस्त लाभार्थियों को ५० % अनुदान।
स. लघु एवं सीमान्त कृषकों के उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त शेष देय धनराशि पर क्रमशः २५% तथा ३३.१/३ % और अनुदान।

आयुक्त एवं प्रशासक
रामगंगा समादेश क्षेत्रविकास प्राधिकारी
[illegible] आजाद नगर कानपुर-२०८ ००२

पराग पॉश्च्युराइज़्ड दूध पीजिए,
दूध की असली शक्ति और भरपूर मज़ा लीजिए।

Pure, Natural, Good Health.

parag
KANPUR SAHKARI MILK BOARD
NIRALA NAGAR (P.W.) KANPUR
पराग

पराग पाश्च्युराइज्ड में डेरी के दूध की भरपूर प्राकृतिक शुद्धता और गुणवत्ता 'पराग' जितना स्वादिष्ट है। उतना ही स्वास्थ्यप्रद। हर प्रकार के भोजन को और मजेदार बनाये। पराग को आज ही अपनायें। और अपने परिवार को दीजिये हर दिन एक स्वादिष्ट तोहफा।

पराग
पॉश्च्युराइज़्ड दूध

उपभोक्ताओं
की जानकारी हेतु

पराग दूध खरीदने
के उपरान्त तुरन्त
गर्म कर लें

सौजन्य से- **लाखन सिंह**
अध्यक्ष
एम.एल. पाठक
महाप्रबन्धक

X-PERT

OPERATION
FLOOD
कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
निराला नगर, जूही कानपुर

श्री किशोरी लाल गुप्त

श्री बलराम नरूला

श्री सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल

श्री संजीव जायसवाल

पड़ रही है। आज भी प्रदेश में उम्दा किस्म का यार्न नहीं बनता। इसे दक्षिण भारत के राज्यों या पंजाब से मंगाना पड़ता है। बिक्री कर की ऊंची दरों के कारण दिल्ली से बड़े पैमाने पर आनेवाला नम्बर दो का होजरी सामान प्रदेश के होजरी उद्योग का स्थायी सिरदर्द बन गया है।

व्यापार मंडल : उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े उद्यमी सुरेन्द्र मोहन अग्रवाल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, "सरकारी विभागों में सामंजस्य एवं समन्वय जैसी कोई चीज है ही नहीं और इसलिए नयी इकाइयां लग तो रही हैं, पर वे नौकरशाही और सरकारी नीतियों की वजह से पलेंगी नहीं। जब तक एकल खिड़की की सुविधा लघु उद्योगों को मुहैया नहीं कराई जायेगी, तब तक सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों-करोड़ रुपए सब्सिडी, औद्योगिक अस्थानों एवं क्षेत्रों के विकास के नाम पर यूं ही बरबाद होता रहेगा।"

श्री अग्रवाल प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार तमाम सरकारी निगमों की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। बिजली, दूरसंचार, परिवहन और सुरक्षा जैसी बुनियादी सहूलियतें जरूरत के मुताबिक उपलब्ध नहीं हैं। इधर सब्सिडी को लेकर प्रदेश के उद्योग जगत में जो हड़कम्प मचा है, उसमे औद्योगिक विकास के भविष्य पर धुंध छा गयी है। करोड़ों रुपए का पूंजी-निवेश नये उद्योगों की स्थापना में हो चुका है। लेकिन सब्सिडी के अभाव में इस भारी भरकम पूंजी-निवेश के मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। सरकार उद्यमियों को अनिश्चय की स्थिति में डाले हुए है। ऐसे में हजारों उद्योग चलने के पहले ही बीमार हो चुके हैं।

पान मसाला : पान मसाला ने तो देश में ही नहीं, विदेश में भी धूम मचा रखी है, लेकिन उभरते पान मसाला युवा निर्माता संजीव कुमार जायसवाल अपनी तकलीफें बयान करते हुए कहते हैं, "केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में पान मसाले पर उत्पाद शुल्क में की गयी वृद्धि से इस उद्योग पर काली छाया मंडराने लगी है। पान मसाले पर पहले से ही खासा कर-बोझ था। उत्पाद शुल्क में हुई बढ़ोतरी से नकली और घटिया दर्जे के पान मसाले के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस उद्योग को बचाने के लिए वह शुल्क दरों में रियायत दे।

जवाहर रोजगार योजना

जिला ग्राम्यविकास अभिकरण कानपुर नगर एवं कानपुर देहात

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या है। भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार प्रदान करने हेतु योजनाऐं समय समय पर चलाई गई हैं। वर्ष 1989-90 से भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया है।

जवाहर रोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं तथा पुरुष बेरोजगारों अथवा पूर्ण कालिक काम न पाने वालों को लाभदायक अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है, साथ ही इसका दूसरा उद्देश्य है, उत्पादक, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो और ग्रामीण आय स्तर में वृद्धि हो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण जीवन स्तर में सुधार हो।

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग लक्ष्य समूह होगा। प्राथमिकता अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के समूहों को दी जानी है। इस योजना की विशेष बात यह है कि योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार सुलभ होगा।

जवाहर रोजगार योजना के संचालन का दायित्व, ग्राम स्तर पर पंचायतों का होगा। ग्राम पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होना है जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम है ऐसी ग्राम सभाओं की जनसंख्या + 1000 मानकर धन आवंटित किया जायेगा।

प्रदीप भटनागर
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर/देहात

के०के० सिंह
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर

नीता चौधरी
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर देहात

हस्तकला एवं व्यवसाय के मध्य
स्वर्णिम भविष्य का सेतु

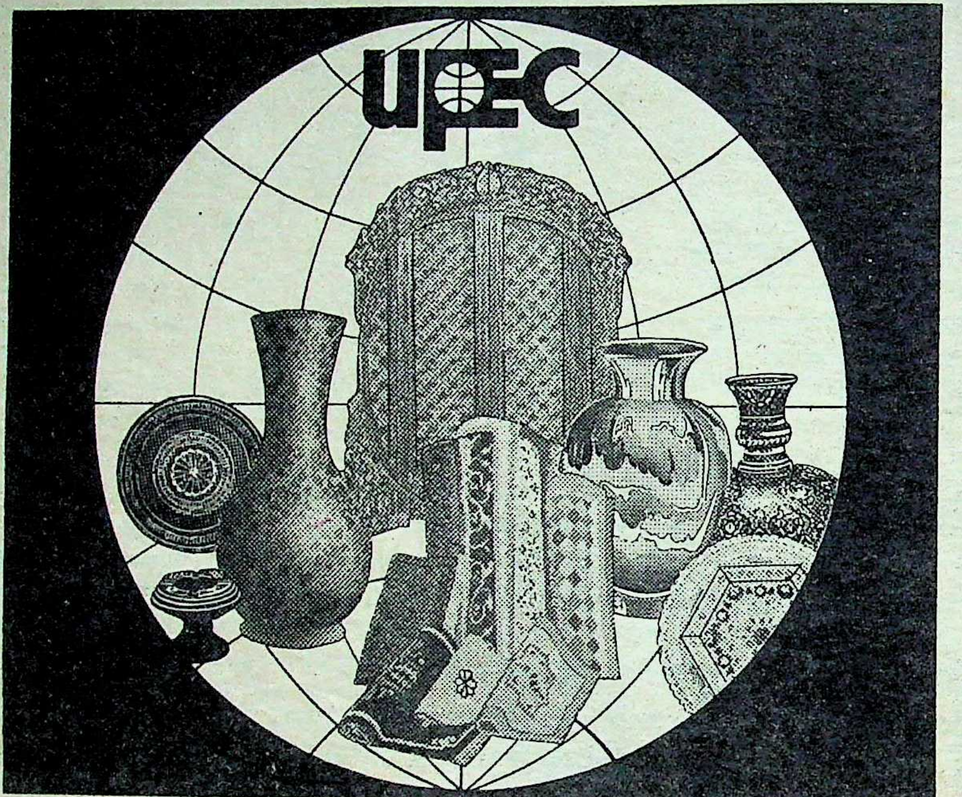

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम हस्तशिल्प उत्पादों के अतिरिक्त प्रदेश की कालातीत हस्तकला उत्पादों को जन-सामान्य में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उनकी विपणन व प्रदर्शन व्यवस्था अपने "गंगोत्री" प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से देश के 12 प्रमुख नगरों में कर रहा है। वर्ष 1988-89 में निगम के व्यवसाय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम चिकन उत्पादन योजना, कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना व काष्ठ तराश प्रभाग जैसी विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से लगभग 2,000 चिकन कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार व लगभग 20,000 से अधिक काष्ठ तराशकों, कालीन बुनकरों, कुम्भकारों, धातुकर्मियों व मूर्तिकारों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रहा है।

किसी उत्पाद की ग्राहयता आतरिक बाजार में परखने के उपरान्त ही उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन व्यवस्था सफलतापूर्वक सम्पादित की जा सकती है। इसी सिद्धान्त के आधार पर निगम ने आंतरिक बाजार में प्रदेश के हस्तनिर्मित उत्पादों की विपणन व्यवस्था में आशातीत सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात हेतु एक नेटवर्क की भी स्थापना की है। इसके अन्तर्गत निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य के प्रतिभा सम्पन्न हस्तशिल्पियों को यूरोपिय देशों, अमेरिका एव सुदूर-पूर्व देशों में अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं व्यापार संवर्धन व अपने उत्पादों हेतु आवश्यक कच्चामाल इत्यादि के आयात हेतु निगम सहायता भी प्रदान करता है। हस्तशिल्प उत्पादों के प्रोत्साहन, प्रचार, व प्रसार इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में निगम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों व क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग लेता है। निगम वाराणसी स्थित "हवाई मालवहन संकुल" के माध्यम से हवाई मालवहन व्यवस्था व विदेशी आयातकों व देश के निर्यातकों को निर्यात संबंधी आवश्यक जानकारी व दिशानिर्देश प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम विश्व सराहना में, उत्तर प्रदेश की कुंजी है।

UPEC
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि.
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
बी-27, सर्वोदय नगर, कानपुर-208 005

गंगोत्री
शोरूम : दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, बैंगलोर, भोपाल, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, कानुपर

NAA/D/UPEC-89

श्री राजेन्द्र मल्होत्रा

श्री एम०एल० पाठक

श्री राजीव कपूर

श्री सुमन कुमार माडवेल

श्री डी०एम० बत्रा

श्री योगेश चन्द्र गुप्त

टीवी उद्योग : पांच वर्ष पूर्व कानपुर और इसके आसपास टीवी का निर्माण करनेवाली सोलह इकाइयां स्थापित हुई थीं, लेकिन सिर्फ दो इकाइयां ही अपने अस्तित्व को कायम रख पायी हैं। आइडियल टीवी के निर्माता एवं युवा उद्यमी राजेंद्र मल्होत्रा मानते हैं कि बिक्री बाद सेवा, गुणवत्ता का अभाव, अनुभव की कमी और बड़े निर्माताओं के मुकाबले कीमतें ज्यादा रखने की वजह से ही ये टीवी इकाइयां ठप हो गयीं। वैसे विपणन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और इससे अंततः गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मल्होत्रा का कहना है, "धार्मिक सीरियलों की प्रस्तुति से टीवी से बाजार को अब बढ़ावा मिला है। गांवों में बैट्री सिस्टम आधारित टीवी सेटों की बिक्री में खासी वृद्धि हुई है, लेकिन अगर सरकार टीवी सेटों पर कर भार कम कर दे, तो एक ओर उपभोक्ता वर्ग को राहत मिलेगी, तो दूसरी ओर टीवी उद्योग के बाजार का विस्तार भी होगा।

दुग्ध उत्पादन : यूनिसेफ की मदद से स्वीडन की बनी मशीनों से लैस कानपुर मिल्क बोर्ड का दुग्ध संसाधन करीब ढाई साल बंद रहने के बाद आपरेशन फ्लड-ए के तहत, फरवरी, १९८४ से पुनः सक्रिय हुआ। शुरू में इसकी दैनिक क्षमता सिर्फ पांच हजार लीटर दूध तैयार करने की थी, लेकिन इस समय यह रोजाना कोई ९० हजार पाली पैक में करीब ४५ हजार लीटर दूध शहर को मुहैया करा रहा है। मिल्क बोर्ड के महाप्रबंधक एमएल पाठक बताते हैं, "उन्नाव, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, जालौन तथा अलीगढ़ से रोजाना कोई ३५ हजार लीटर दूध हासिल करके शहर के ५०० बिक्री केंद्रों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है।"

श्री पाठक के अनुसार, "बोर्ड ने गत वर्ष करीब दस करोड़ रुपए का व्यवसाय करके अपनी वित्तीय स्थिति सुधारी है। इस साल ११-१२ करोड़ रुपए के बीच कारोबार होने की उम्मीद है। बोर्ड को अब तक के इतिहास में पिछले तीन वर्षों से मुनाफा हो रहा है, लेकिन बोर्ड को हुए कुल दो करोड़ रुपए के घाटे की अभी भरपायी नहीं हो पायी है।"

पाठक को उम्मीद है कि आनेवाले वर्षों में वे इस घाटे को समाप्त कर देंगे, क्योंकि क्षमता-विस्तार के साथ-साथ बोर्ड दूध, घी, मक्खन के अलावा खोये और पनीर का भी उत्पादन कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार से जितनी मदद मिलने की उम्मीद थी, वह उन्हें नहीं मिल पा रही।

स्कूटर उद्योग : निजी क्षेत्र की स्कूटर कंपनी एलएमएल ने कानपुर को न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में ला दिया है। इसके मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव राजीव कपूर का कहना है कि मोपेड की तरह स्कूटर भी मध्यम वर्ग का वाहन है, अतः स्कूटर पर भी उत्पाद शुल्क २५ के बजाय १५ प्रतिशत किया जाना चाहिए। एलएमएल कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, बंगलादेश, कुवैत, टर्की, सूडान तथा जापान सरीखे देशों को स्कूटर निर्यात कर रहा है।

एलएमएल में इस वक्त कुल करीब ३००० कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी मदद से इस वर्ष इस कम्पनी ने १ लाख, ८० हजार स्कूटर का निर्माण कर २८० करोड़ रुपए का कारोबार किया है। १९८४ में जब यह प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था, तो प्रतिमाह दस हजार स्कूटर का निर्माण होता था जो अब बढ़कर १५ हजार हो गया है तथा चालू वर्ष के समाप्त होते-होते यहां २० हजार स्कूटरों का प्रतिमास निर्माण होने लगेगा। स्कूटर का करीब ९८ प्रतिशत स्वदेशीकरण किया जा चुका है जबकि स्कूटर बाजार में इसकी हिस्सेदारी अब २३ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

प्रदेश के प्रमुख इस्पात पाइप निर्माता एवं निर्यातक एस बत्रा का कहना है, "लाल फीताशाही पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उद्योग से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं का और सरलीकरण करने की तत्काल आवश्यकता है, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर बढ़ावा मिलना चाहिए।"

होटल उद्योग से जुड़े विनय महरोत्रा का कहना है, "एक मई से वीडियो लाइसेंसिंग (प्रति टीवी सेट १५ रुपए प्रति सप्ताह) शुरू कर दिये जाने से होटल उद्योग परेशान है। अधिकांश ने ग्राहकों को वीडियो सुविधा देना बंद कर दिया है, जिससे कारोबार पर चोट लग रही है। एक जून से होटल उद्योग पर लगा १०-२० प्रतिशत का व्ययकर इस उद्योग की हालत और खस्ता कर देगा।"

उप्र उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र प्रदेश सरकार की बिक्री नीति में आमूल-चूल परिवर्तन के हिमायती हैं। श्री मिश्र का कहना है, "बिक्री कर की ऊंची दरों से प्रदेश का व्यापार संकुचित होता जा रहा है। सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिल रहा है और उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं।

१९४४ से सक्रिय इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ नार्दर्न इंडिया के अध्यक्ष एवं उद्योगपति श्री केपी वैद्य का कहना है, "लघु उद्योगों के लिए पूंजी-निवेश सीमा (उपकरण व मशीनरी) ३५ लाख रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम ६० लाख रुपए की जानी चाहिए, क्योंकि बिजली उपकरणों के दाम दो साल के अंदर दो से तीन गुना तक बढ़ गये हैं। फिटिंग-फिक्चर्स विशेषकर केबिल की कीमतों में इस बीच चार गुना तक वृद्धि हुई है। यही नहीं

HERE THERE AND EVERYWHERE

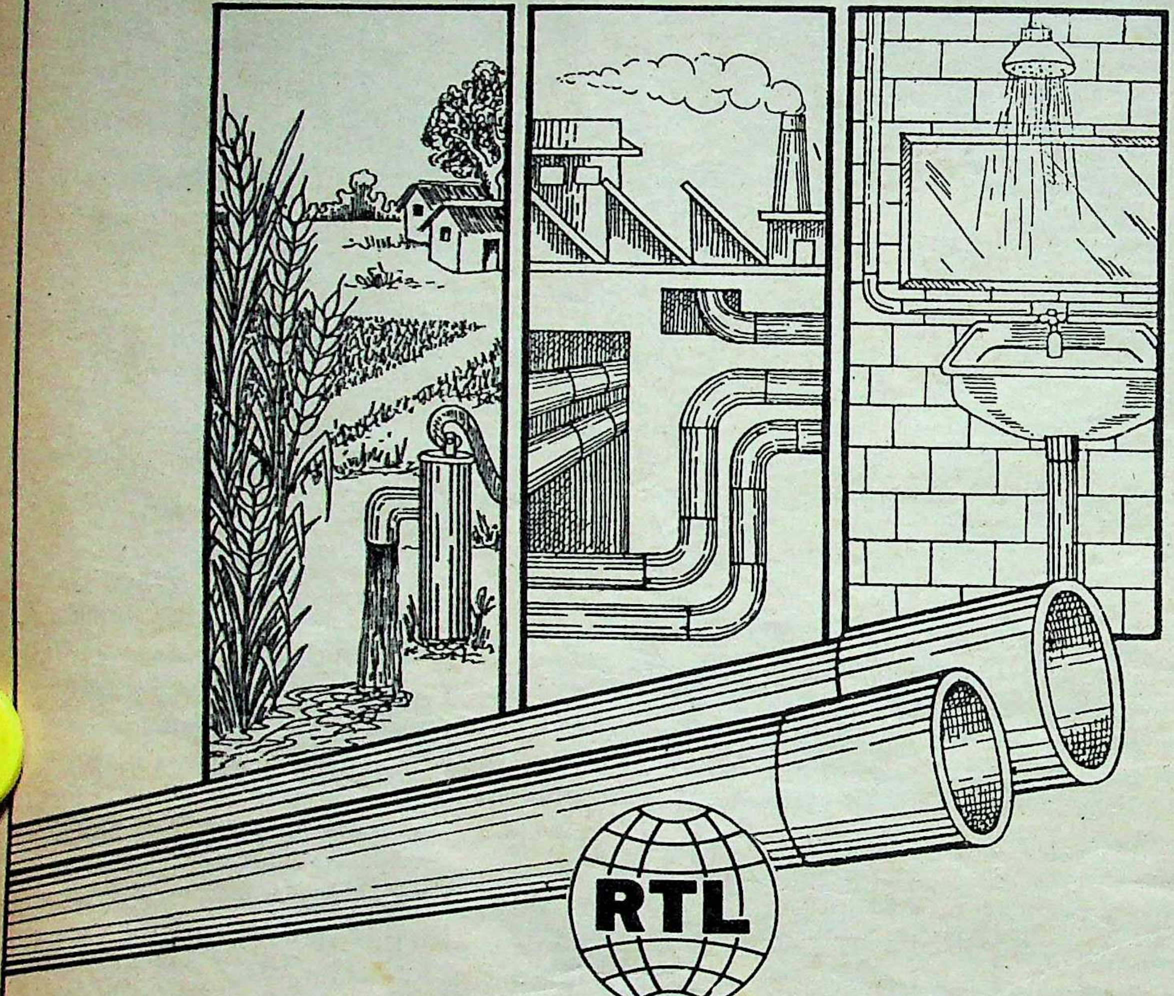

STEEL TUBES & PIPES

ARE KNOWN FOR :

QUALITY, DURABILITY AND TECHNOLOGICAL EXCELLENCE

Manufacturers & Exporters :

R RAJINDER TUBES LIMITED

'Rajinder House', 117/H-1/303, Model Town, Pandav Nagar, Kanpur-208 005
Gram : 'Tubemaker' Phones (PBX) 21-6605, 21-5881, 21-8160 Telex :0325-299 RTL IN
Branches & Representations : Ahmedabad* Bombay* Calcutta* Chandigarh* Delhi

BHARAT

THE MANUFACTURERS OF UTTAR PRADESH ARE INVITED TO JOIN QUALITY MARKING SCHEME (QMS) OF UTTAR PRADESH GOVERNMENT

The Uttar Pradesh Government is providing 'Q' mark on the products being manufactured according to the I.S.I. specifications or on the Handicrafts being produced according to the specifications drawn by the Director of Industries.

Hence insists on 'Q' marked goods.

'Q' MARK IS AN ASSURANCE OF QUALITY IS PER INDIAN STANDARDS.

Q MARK CREATES CONFIDENCE IN CONSUMERS BY ENSURING QUALITY, STANDARD, DURABILITY, DEPENDABILITY, RELIABILITY OF MATERIALS, AND GENUINENESS AND CAN BE TRUSTED UPON.

FOR THIS PURPOSE QUALITY TESTING IS DONE THROUGH A CHAIN OF TESTING CENTRES AND IN COLLABORATION WITH I.S.I. APPROVED LABS VIZ. IIT, KANPUR, ENGG. UNIVERSITY OF ROORKEE AND VARIOUS ENGINEERING COLLEGES IN THE STATE. THE FOLLOWING GOODS ARE QUALITY MARKED AT OUR DEPOTS/TESTING CENTRES AT :—

1) Drawing and Surveyings instruments, Roorkee
2) Hand Prints, Farrukhabad/Lucknow
3) Gold Thread, Varanasi
4) Woollen Carpet, Mirzapur, Varanasi and Shahjahanpur
5) Leather Goods, Kanpur
6) Hosiery goods, Kanpur
7) Agricultural Implements. Meerut
8) Sports Goods, Meerut
9) Chikan, Lucknow
10) Electrical Goods, Kanpur, Varanasi
11) Locks, Aligarh
12) Building Fitting Materials, Aligarh
13) Scissors and Razors, Meerut
14) Diesel Engine, Ghaziabad
15) Wooden Furniture, Bareilly Allahabad
16) Wood Carving, Saharanpur
17) Marble Goods, Agra
18) Cycle Parts, Kanpur, Lucknow, Varanasi
19) Zari Goods, Agra
20) Pucca Kalai, Moradabad
21) Art Metal, Moradabad

The 'Q' mark products are being given the same preference in the State Government purchases as are available for I.S.I. marked products.

It you are quality conscious and manufacturing quality products, come and join, Quality Marking Scheme of U.P. Government and assure consumers' of your Quality and ensure good business for yourself.

DEVI DAYAL
COMMISSIONER AND DIRECTOR OF INDUSTRIES
(QUALITY MARKING SCHEME)
UTTAR PRADESH GOVERNMENT.

उ०प्र० लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर

प्रदेश के लघु उद्योगों के प्रगति व विकास में
विगत ३० वर्षों से सेवा में तत्पर :—

हमारा उद्देश्य आपके व्यवसाय की समृद्धि व विकास। आपके व्यवसाय और समृद्धि के संवर्धन हेतु यह निगम अधोलिखित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है—

१-कच्चा माल (लौह तथा अलौह)
२-मशीनों का किराया क्रय
३-आयात सहायता
४-कोयला व कोक
५-विपणन सहायता
६-तकनीकी तथा परियोजना परामर्श
७-छोटे बुनकरों को ऊनी धागे की आपूर्ति
८-पिछड़े जिलों में संयुक्त उद्योग परियोजना
९-अभिलेख केन्द्र व तथ्य विवरण (डाटा बैंक)
१०-अपनी सहायक यू०पी०एस०आई०सी० पाटरीज के माध्यम से
पाटरीज व सिरेमिक्स का विकास
११-विभागीय व्यवसायिक इकाईयां-(अ) वुडसीजनिंग प्लान्ट, इलाहाबाद,
(ब) स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, देहरादून (स) चिनहट पाटरीज , चिनहट
(द) आई०यू०सी०डी० प्लास्टिक फैक्ट्री, कानपुर
१२-सहायक (एन्सीलरी) इकाईयां व काम्पलेक्सेस्
१३-औद्योगिक आस्थानों के निर्माण सम्बन्धी कार्य

विस्तृत विवरण हेतु सम्पर्क करें या लिखें :—
उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०,
११०, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-२०८०१२
दूरभाष-२२०२२७, २२०३५३, २२०९५७.

या

क्षेत्रीय कार्यालय—आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, वाराणसी।

या

हमारे भण्डार—आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बस्ती (प्लास्टिक), फिरोजाबाद (कोयला), गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, महारनपुर (कोयला), मेरठ, वाराणसी, नोयडा

J. K. Synthetics LTD.

J.K. STAPLE & TOWS

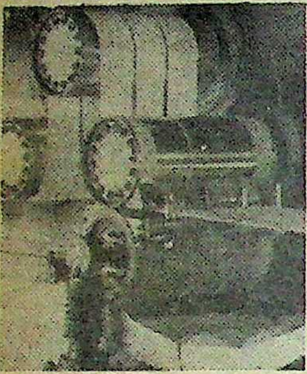

By 1971, Synthetic Fibre had taken the textile market by storm. Foreseeing excellent growth prospects for the industry, J.K. Synthetics set up J.K. Staple & Tows in the same year.

J.K. WHITE CEMENT

The quality of white cement manufactured has been widely acclaimed and well received by the users. The plant is computerised with on-line X-Ray analysers for proper control of raw material composition and kiln parameters maintenance.

ENERGY & ENVIRONMENT DIVISION

In the realm of harnessing non-conventional sources of energy, this division has come a long way. Having been the FIRST in the country to instal a large-sized Wind Electric Generator in Gujarat, today it is executing wind farms at Talcauvery in Coorg Distt. and at many other places in India. Plans are afoot to manufacture these generators in India.

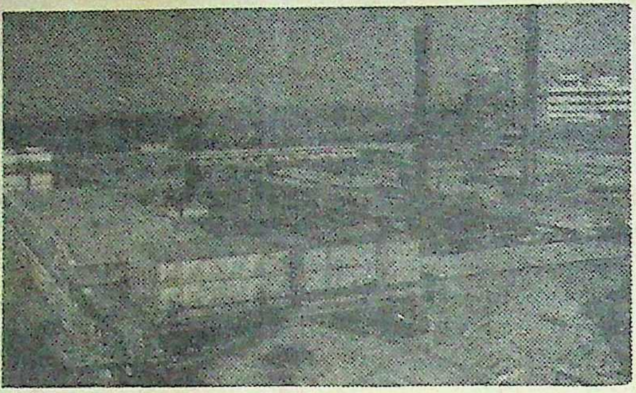

VISION During the last 25 years, J.K. Synthetics Ltd. (JKS) has put many a Silver Lining on the Industrial Horizon of India. And that too as Pioneers! Among the array of JKS many Firsts are: Synthetic Nylon fibre industry Acrylic fibre manufacture DMT monomer from polyester waste, Differentially dyeable nylon, Cationic dyeable polyester and hollow polyester fibre, Wind generator, white cement and others.

CONCERN FOR HUMAN WELFARE Human Concern is at the heart of the concept of Welfare, which has to be seen to be believed as practised at the multicrore Corporation—JKS.

Schools and Hospitals with excellent facilities, places-of worship, encouragement to recreation and sports are well provided for. JKS patronises and promotes national level tournaments. JKS knows that a healthy man creates a healthy structure. Based on this it has established the Jaykaylon Women's Hospital, Mother and Child Health Institute at Jaipur. Paediatric Hospital, Jaykaylon Sports Pavillion, Gopal Krishna Singhania Badminton Hall, Open Air Auditorium, Super Markets, Co-operative Societies, etc., it has established schools at Kota and Nimbahera where it has a large work-force.

JAYKAY TECH

Jaykay Tech had originally been the project wing of J.K. Synthetics Ltd. with 15 years of experience in implementing projects in a wide range of fields, including Synthetic Fibres, Chemicals, Petrochemicals, Thermoplastics, Cement, Thermal Power Plants and Non-conventional Energy Equipment.

J.K. CEMENT

Looking at growth prospects, the company diversified into the manufacture of grey Portland Cement. A separate division came into being under the name of J.K. Cement Works. A plant was established at Nimbahera, Dist. Chittorgarh (Rajasthan) in May 1974.

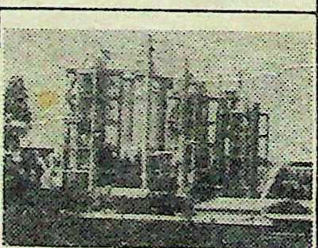

J.K. TECHNOSOFT

J.K. Technosoft (JKT) is the software division of J.K. Synthetics Ltd.

JKT is involved in the development of customised software, providing consultancy for computerisation and other related areas. Currently, JKT has vast and varied experience of executing several projects in India & abroad.

PADAM SYNTHETICS

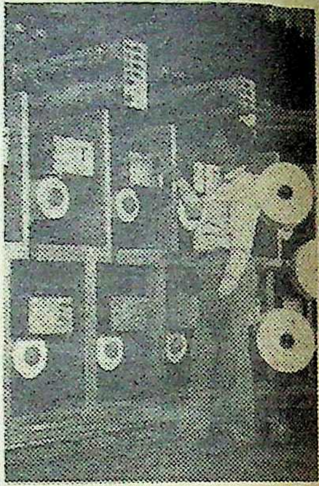

Of the 5 divisions in the Kota Complex, Padam Synthetics has grown tremendously in size, consequently increasingly its production of Nylon and Polyester Yarn manifolds.

Latest technologies had been incorporated as Padam Synthetics expanded its capacity. In March 1986 a new unit was added to Padam Synthetics (in collaboration with an acknowledged hitech company of Europe) to produce a better quality of Polyester Filament Yarn.

Sir PADAMPAT RESEARCH CENTRE

With the objective to develop new and better products and provide technical backup for the various production units—Sir Padampat Research Centre (SPRC) was established in 1973.

The organisation was honoured by the Indian Merchants Chamber in 1980. It has also won the Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry Award for excellence in Research.

"With the vision and confidence in its resources and skills, J.K. Synthetics is striding towards the 21st Century. Routes will be many and varied, but the focus will unwaveringly be on the pursuit of excellence. The inherited virtues and values of the past will doubtlessly put their imprint on the future."

Giving our best. Because we care

JAYKAY

adEnvoys

श्री देवी दयाल

श्री अशोक कुमार

श्री जगजीत सिंह

सुश्री सुनन्दा प्रसाद

श्री ललित श्रीवास्तव

श्री आर०एन० तिवारी

जेनरेटिंग सेटों के दाम एक साल के अंदर ३५ से ४० फीसदी बढ़े हैं।

समस्याओं का निराकरण : कानपुर के उद्यमियों की समस्याएं प्रदेश भर के उद्यमियों की समस्याएं है और ऐसा भी नहीं है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में 'मार्च, १९८९' से 'जनपद लघु उद्योग बंधु की स्थापना की है, ताकि औद्योगिकीकरण की गति को तेजी मिले। उद्यमियों की अड़चनों को दूर करने के लिए उद्योग बंधु की हर महीने बैठक होगी, जिसमें बिजली, वित्त, श्रमं, प्रदूषण-नियंत्रण आदि सभी संबंधित महकमों के अफसर शामिल होंगे। लघु उद्योगों के लिए वर्तमान पूंजी सीमा ३५ लाख रुपए से अधिक करने के प्रश्न पर योजना आयोग लघु क्षेत्र को दो भागों—लघु व लघुतर में विभक्त करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अधिकाश लघु इकाइयों में दो लाख रुपए के इर्द-गिर्द पूंजी निवेश होता है। उद्योग निदेशक देवीदयाल के अनुसार मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए नयी औद्योगिक नीति तैयार करा रहे हैं, ताकि आनेवाली आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन लाख नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रदेश में हो सके। उद्योग निदेशक स्वीकार करते हैं कि सब्सिडी समाप्त होने से औद्योगीकरण की रफ्तार सुस्त हुई है, लेकिन वे यह भी जानकारी देते है कि प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान खोज रही है और मुख्यमंत्री इस संबंध मे केंद्र से लिखा-पढ़ी कर रहे है।

इस वक्त प्रदेश में बिजली की उपलब्धता आवश्यकता से करीब बीस प्रतिशत कम है। छठी योजना में बिजली की स्थापित क्षमता ४४०० मेगावाट थी, जिसे सातवी योजना में बढ़ाकर ६८०० और आठवीं योजना में ११५०० मेगावाट करने की योजना है।

उद्यमियो की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय उत्तर प्रदेश वित्त निगम न केवल अन्य राज्यों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा है बल्कि ऋण प्रक्रिया को सरल करने के साथ-साथ उसने १९८९-९० वर्ष में १६० करोड़ का ऋण देने और १४० करोड़ की सहायता राशि वितरित करने का लक्ष्य बनाया है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने आगामी तीन सालों के अंदर तीस नये औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने के उद्देश्य से १२ हजार एकड़ जमीन हासिल करने की योजना बनायी है। प्रदेश के जिन सात मैदानी और चार पर्वतीय जिलों में कोई उद्योग नहीं है, वहां भी औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ४२०५ एकड़ में से ४ हजार एकड़ जमीन हासिल कर चुका है तथा इस योजना पर वह १५ करोड़ रुपए खर्च भी कर चुका है। निगम के प्रबंध निदेशक ललित श्रीवास्तव उक्त योजनाओं के बल पर ही दावा करते हैं कि आनेवाले तीन चार वर्षों में उत्तर प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक राज्य बन जायेगा, लेकिन तथ्य यह है कि सरकार की अधिकाश ठोस योजनाएं भविष्य के गर्भ में हैं. फिर भी यदि इन योजनाओं पर ईमानदारी से काम हुआ तो कोई वजह नहीं कि उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर न हो।

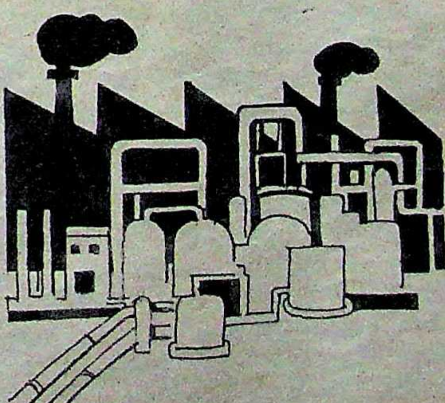

जहा तक कानपुर शहर की समस्याओं का सवाल है, इस संबंध में 'माया' ने नवगठित कानपुर कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर बीबी सिन्हा, सत्रह वर्षों बाद जनप्रतिनिधियों के हाथों में आयी नगरमहापालिका के महापौर श्रीप्रकाश जायसवाल, कानपुर जल संस्थान के महाप्रबंधक यज्ञदत्त मिश्र, कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डीसी लाखा, कानपुर नगर व देहात दोनों जिलो के मुख्य विकास अधिकारी प्रदीप भटनागर से बातें की हैं। उक्त सभी अधिकारियों के पास अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित विकास की लम्बी-चौड़ी योजनाएं हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कानपुर शहर और देहात भी पानी, बिजली, यातायात, आवास, प्रदूषण आदि विभिन्न समस्याओं से बड़ी जल्दी निजात पा जायेगा। कानपुर के उद्यमी, कर्मचारी, शहरी और ग्रमीण क्षेत्रों के लोग बड़ी बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अभी तो कानपुर की स्थिति यह है कि जहां हरियाणा जैसे राज्य प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का जश्न मना चुके है, वही औद्योगिक नगरी कानपुर के नगर-जनपद के २६१ गावों में से ९४ गांवों और देहात जनपद के १७६२ गांवो में से ११०४ गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। शहरी और देहात क्षेत्र के कुल २०२३ गांवो में से ३८२ गांव ऐसे हैं जो अभी तक पक्की सड़कों से पांच किलोमीटर अधिक दूरी पर स्थित है। ●

—विनोद मिश्र के साथ प्रणतेश बाजपेयी

किसान आंदोलन

मुख्यमंत्री चौधरी फिर सांसत में

सत्ता-पक्ष के भीतरी असंतोष और विरोध से परेशान मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी चुनाव सिर पर होने का लाभ पा गये और उनकी कुरसी छिनने का संकट फिलहाल टल गया। लेकिन इसी समय किसानों ने निर्णायक आंदोलन छेड़ने की धमकी देकर उनकी नींद हराम कर दी है। यह धमकी असंतुष्टों और विरोधियों की गतिविधियों से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। आखिर, किसानों से इतने भयभीत क्यों हैं अमरसिंह चौधरी?

लगता है सांसत, गुजरात के मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी की नियति बन गयी है। जीना दूभर कर देनेवाली एक सांसत—अपने काबीनाई और विधानमंडलीय साथियों-सहयोगियों के चक्रव्यूह—से उबर कर वे चैन की सांस भी नहीं ले पाये थे कि दूसरी सांसत में पड़ गये। यह सांसत किसान आंदोलन की उठती हुई आंधी है, वह खौफनाक आंधी जिसने डेढ़ साल पहले चौधरी मंत्रिमंडल को झकझोर डाला था। इसीलिए यह मुख्यमंत्री के लिए एक मुकम्मल सांसत बन गयी है।

गुजरात में किसानों का मुद्दा बड़ा नाजुक है, खासकर मुख्यमंत्री के लिए। बिजली, खाद, खेती के काम आनेवाली दूसरी चीजों की आसमान छूती कीमतों से आजिज आये किसानों ने सरकार की नीति-रीति के खिलाफ फिर कमर कस ली है। अब अगर इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है, तो इसका अंजाम राज्य से कांग्रेस-इ की विदाई की शक्ल ले लेगा और अगर किसानों की मांगें मान ली गयीं, (जिसके आसार नहीं के बराबर ही हैं) तो 'बड़े किसानों के दलाल' होने का कलंक अनायास ही चौधरी के चेहरे पर चस्पा हो जायेगा। कांग्रेस-इ के अंदर ही चौधरी की जड़ खोद रहे लोग और विपक्ष वाले बड़ी चौकसी के साथ ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं।

दुधारी तलवार: असंतुष्ट कांग्रेसी, मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपए की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि १९८७ में सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को साढ़े ग्यारह करोड़ रुपए की बिजली शुल्क में रियायत दी थी और १९८६ में ग्रामीण उपभोक्ताओं को ५३.७५ करोड़ की सहायता मुहैया की थी। "ऐसा धनी किसानों को खुश करने के लिए किया गया था, यद्यपि इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ।" एक असंतुष्ट नेता कहते हैं।

चौधरी के लिए मौजूदा आंदोलन इस चुनावी वर्ष में इसलिए दुधारी तलवार साबित होगा, क्योंकि किसान मानते हैं कि सरकार ने डेढ़ वर्ष पूर्व उनकी मांगें स्वीकार करने के बावजूद उन पर अमल न करके धोखाधड़ी की है। इस बार किसान समझौता-वार्ता में शामिल होंगे, इसमें भी संदेह है।

गांधी नगर तालुका के इसानपुर गांव के एक छोटे किसान रामचंद्र पटेल बताते हैं, "बिजली की ऊंची दरें हम छोटे किसानो की कमर तोड़ रही हैं। हमारे गांव का जलस्रोत बहुत नीचे है, इसलिए हमें ज्यादा शक्तिशाली मोटरों से पानी निकालना पड़ता है और अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिण गुजरात के किसान कम शक्तिवाली मोटरों से महज ५०० फुट नीचें से पानी निकाल लेते हैं। सरकार ने इस बारे में कार्रवाई करने का वायदा किया था, किंतु अभी तक किया कुछ नहीं।"

किसानों का मानना है कि मोटर के हार्सपावर (एचपी) के अनुसार तय की गयी बिजली-दरें बहुत ऊंची हैं। उत्तर गुजरात के बंसकठा जिले के एक किसान अशोक चौधरी ने 'माया' को बताया कि सरकार ने ७.५० एचपी तक की मोटर के लिए १९२ रु०, ७.५० से लेकर १० एचपी मोटर के लिए ३६० रु० और १० एचपी से ऊपर के लिए ५०० रु० तय किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की भौगोलिक संरचना किसानों की इस दलील को तर्कसंगत करार देती है कि गुजरात में बिजली-दर का ढांचा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के समान बनाया जाये। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्रों की जमीन पथरीली है और जलस्रोत बहुत नीचे है। इन क्षेत्रों में उच्च शक्तिवाली मोटर लगाकर ही बहुत नीचे से पानी निकाला जा सकता है। ठीक विपरीत दक्षिण गुजरात में ५०० फुट नीचे से कम शक्तिशाली मोटर पानी निकाल लेती है। "उत्तर गुजरात या सौराष्ट्र के किसान अधिक क्यों अदा करें?" अशोक चौधरी सवाल करते हैं।

"हमने भारतीय किसान संघ (भाकिस) के तहत अपना आंदोलन फिर शुरू करने का फैसला किया है। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।" पटेल जोर देकर कहते हैं। इस बीच भाकिस ने अपना संघर्ष कार्यक्रम तैयार कर लिया है जिसमें बिजली बिल सहित अन्य सरकारी बकायों की 'अदायगी बंद' करना भी शामिल है। स्मरणीय है कि गुजरात बिजली बोर्ड (गुबिबो) १९८६-८७ में तब संकट में पड़ गया था जब इसी प्रकार के 'अदायगी बंद' कार्यक्रम से उसे ६७ करोड़ रु० की भारी भरकम बकाया रकम माफ करनी पड़ी थी।

किसानों का मलाल: भाकिस ने अपना मंशा जाहिर कर दिया है। २९ मई के इसके गांधीनगर राज्य सम्मेलन में संघ के शीर्ष नेताओं, श्यामसुंदर द्विवेदी और बालकृष्ण पांडे, ने ऐलान किया था, "किसान अपनी मांगों के लिए गिड़गिड़ायेगा नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा।" भाकिस के इस आक्रामक रुख से सरकार सकते में आ गयी है। मुख्यमंत्री चौधरी इस समय लोहा लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि, उनके सामने अपनी कुरसी बचाने की समस्या के साथ-साथ लगातार तीन साल सूखा पड़ने के बाद राज्य के आर्थिक विकास का सवाल भी है। मौजूदा स्थिति में किसान समुदाय यदि मैदानेजंग में दुबारा उतर आया है, तो इसके लिए वह नहीं, सरकार ही कुसूरवार है। क्योंकि उसने किसानों की लगभग तमाम मांगों को जायज करार देते हुए मंजूर तो जरूर किया था, मगर अमल क्यों नहीं किया, यह स्पष्ट नहीं किया। कुछ भी हो, इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं।

गुजरात में रासायनिक खाद की दरों की तुलना चंद अन्य उत्तरी राज्यों से करते हुए अशोक चौधरी ने बताया कि ५० किग्रा यूरिया बैग हिमाचल प्रदेश के किसानों को ७६ रु० में, हरियाणा, पंजाब में ९८ रु० में उपलब्ध हैं। किंतु गुजरात के किसानों को वह १२३.८० रु० में मिलता है। इस प्रकार दरों में ४० प्रतिशत का फर्क है। जबकि अधिकांश रासायनिक खादें गुजरात में ही इफ्क. में बनती हैं। अशोक दलील

पेश करते हुए कहते हैं, ''इससे कृषि-दरों में भारी फर्क पड़ता है। हमारे क्षेत्र के किसान को अपने खेत में फसल उगाने के लिए जहां ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है, वहीं कुछ सौ किमी दूर के किसान को कम रकम लगानी पड़ती है। उत्तर गुजरात में एक एकड़ फसल की लागत १६०० रु० है और दक्षिणी गुजरात में महज १५० रु० है।'' उनके अनुसार भाकिस ने इस फर्क को मद्देनजर रख उत्तर गुजरात के किसानों के लिए जिस रियायत की मांग की है, उसे सरकार ने ठुकरा दिया है। इसके लिए किसान अभी भी संघर्षरत हैं।

पिछली बातचीत में सरकार ने यह मांग भी मानी थी कि किसानों के खिलाफ आतंकवाद व विध्वंसक गतिविधियां कानून (टाडा) के तहत जारी तमाम मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे। किसान नेताओं का दावा है कि ऐसे ४० प्रतिशत मामले अभी भी वापस नहीं लिये गये हैं।

किसानों को अपनी ताकत का अहसास: भाकिस नेता श्याम सुंदर द्विवेदी मंच पर

एक अन्य मुद्दा शहरी भूमि हदबंदी कानून (यूएलसी) की विचित्र धारा ८४ (सी) का है जो किसानों को अपने गांव से ८ किमी दूर की जमीन खरीदने की इजाजत नहीं देता। किसान नेता मिसाल देते हैं कि जो ५०० परिवार बांध-निर्माण अथवा भूमि के कटाव-अनुपजाऊपन के कारण अपने गांव छोड़ने को विवश हुए थे और जिन्हें सरकार से अन्यत्र भूमि खरीदने के लिए मुआवजे मिले थे, वे अहमदाबाद से २५ किमी दूर देहगम में बस गये थे। उन्हें अब यूएलसी की धारा ८४ (सी) के तहत नोटिसें मिली हैं। किसान इस धारा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

भाकिस की एक अन्य मांग है कि केंद्र २४० करोड़ रु० का फसल बीमा फौरन जारी (रिलीज) करे। अभी तक महज १०४ करोड़ ही जारी हुए हैं और वह भी किसानों तक नहीं पहुंचे। किसान नेता मांग कर रहे हैं कि शेष रकम ब्याज सहित किसानों में बांटी जाये।

उल्लेखनीय है कि किसानों के गत आंदोलन (१९८७) के दौरान हुए समझौते के बाद मांगों पर विचार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उसने अपनी कार्यवाही पूरी करने के लिए डेढ़ वर्ष लगाया था। किंतु सरकार ने उसकी (समिति की) सिफारिशों पर भी अमल नहीं किया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि मुख्यमंत्री कदाचित कांग्रेस के लिए इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक लाभ की रणनीति के तहत घोषणा में देर कर रहे हैं। उधर किसान मानसून आ जाने के कारण फिलहाल बोवाई आदि में संलग्न है। किंतु भाकिस ने कुछ ही दिनों में आंदोलन को धारदार बनाने की भी रणनीति बना रखी है।

पूर्व अनुभव: रणनीति चाहे जो हो, किंतु १९८७ के उस किसान आंदोलन की आवृत्ति कोई नहीं चाहेगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन पूर्णतया अस्तव्यस्त हो गया था। स्थिति यह थी कि दूध, सब्जी तथा अन्य कृषि जिंसों की गांवों से आपूर्ति पर महीनों प्रतिबंध था। इसका फौरी असर शहरों पर भी पड़ा था। सरकार पड़ोसी राज्यों से भी जिंसें मंगाने में नाकाम रही थी, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों ने राजपथों पर धरना देकर सड़क परिवहन ठप कर दिया था। सरकार ने आंदोलन समाप्त करने के लिए हर हथकंडा भी अपनाया था। हजारों पुलिस जवानों को सड़क-बाधाएं हटाने के लिए तैनात किया गया था, किंतु सफलता नहीं मिली थी। निर्दोष किसानों पर पुलिस ने आतंक भी ढाया, किंतु एकजुट किसान टस-से-मस नहीं हुए थे। उस दौरान दो 'जेल भरो' कार्यक्रमों में २० हजार महिलाओं सहित २८८००० किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थीं।

उक्त आंदोलन ने १६ मार्च (१९८७) को तब हिंसक मोड़ ले लिया था जब राज्य विधानसभा भवन का घेराव करने जा रहे किसानों को गांधी नगर में प्रवेश से रोका गया। राजधानी से २ किमी दूर पेठापुर पुलिस चौकी के पास दो किसान तड़के पुलिस गोलियों का निशाना बने थे। उसी दिन दोपहर को नड़ियाद तालुका के पीपलोद पुलिस चौकी के पास पुलिस फायरिंग में दो अन्य किसान मारे गये थे।

मुखर विद्रोह: इस बार राज्य के किसानों ने १६ से २१ जून तक विभिन्न जिलों और तालुकों में बाजार और सहकारी समिति कार्यालयों पर धरना दिया, सभाएं और रैलियां आयोजित कीं। इस प्रदर्शन में किसानों की उपस्थिति भाकिस नेताओं के लिए काफी उत्साहजनक रही, बावजूद इसके कि बारिश के साथ ही खेती में उनकी व्यस्तता बढ़ गयी थी। पर्यवेक्षक मानते हैं कि राज्य सरकार न तो किसानों को संतुष्ट कर सकती है, न ही किसानों की शिकायतों को झुठला सकती है। लिहाजा, देर-सबेर किसान-आंदोलन का भड़कना लगभग तय है।

दूसरी ओर राज्य के संसदीय तथा विधानसभाई क्षेत्रों के तमाम स्थानीय इंका नेता और कार्यकर्ता विद्रोही तेवर अपनाये हुए हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस महासमिति के पर्यवेक्षकों—श्री भंडारी, गुरुनाथ कुलकर्णी, श्रीमती सुधा जोशी, जाद खां, भरत बिद्रा—ने इन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया। ऐसी खबरें आती रही हैं कि पार्टी के स्थानीय नेताओं—कार्यकर्ताओं ने अधिकांश वर्तमान सांसदों और विधायकों (चाहे वे मुख्यमंत्री के पक्षधर हों या विरोधी) के खिलाफ भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाये और चेतावनी दी कि यदि अगले चुनावों में इन लोगों को टिकट दिये गये, तो पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। इस मुखर विद्रोह से मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी और प्रदेश पार्टी प्रमुख प्रबोध रावल, दोनों परेशान बताये जाते हैं। वे एक ओर इन खबरों को निराधार करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इस विद्रोह के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसी बीच राज्य की समन्वय समिति की एक आवश्यक बैठक में शामिल होने के लिए चौधरी और रावल अत्यअल्पकालिक सूचना पर २४ जून को दिल्ली पहुंचे। इस्पात राज्यमंत्री एमएल फोतेदार की अध्यक्षतावाली इस समिति के दो अन्य सदस्य हैं, चिंतामणि पाणिग्रही और शीला दीक्षित। इस समिति ने गुजरात में नेतृत्व-परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दे दी है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय योजनामंत्री माधवसिंह सोलंकी और दक्षिण गुजरात के महारथी जीनाभाई दारजी द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिये जाने की खबर थी, और यह भी कि राजीव गांधी चुनाव तक यथास्थिति बनाये रखना चाहते हैं। किंतु इस डांवाडोल स्थिति में अगर किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया, तो क्या यथास्थिति बनी रह सकेगी?

—ब्रायन पार्कर

बदहवास राजनीति

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी, तो मूपनार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी छोड़नी पड़ी। अब आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए अटकलें गर्म हैं कि मूपनार अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए करुणानिधि को राजीव गांधी से हाथ मिलाने के लिए राजी करने में जुट गये हैं, तो दिल्ली के सामने सिर झुका चुकीं जयललिता के बारे में कहा जा रहा है कि वे इलाज के बहाने बंगलोर में रह कर हेगड़े से गुफ्तगू करने में व्यस्त रहीं। तमिलनाडु की राजनीति में दुश्मनों को दोस्त बनाने का खेल क्या फिर से शुरू हो गया है या ये सब महज अफवाहें हैं?

भूमिगत होने की राजनीति : जयललिता

मद्रास में इन दिनों एक अद्भुत रस का नाटक चल रहा है। सब-के-सब चिंतित हैं, बेचैनी में हकलाकर बतियाने लगे हैं, मानो राजनीतिक क्षेत्र पर कयामत का साया देखकर दहल गये हों। खाने की मेज हो, ढाबा-चौका हो या दस-बीस लोगों के जमावड़े की कोई और जगह, वे एक ही मुद्दे पर बहसते-फुसफुसाते दिखते हैं—मद्रासवालों के जेहन को कुरेदनेवाली बहुचर्चित महिला जयललिता के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने के मुद्दे पर। अन्नाद्रमुक (जिसकी बागडोर वे संभालती रही हैं) के कर्ताधर्ता बताते हैं, "मैडम लापता नहीं हुई हैं। मैडम बंगलोर में हैं, इलाज करा रही हैं और जल्द ही वहां से आकर पार्टी का संचालन करने लगेंगी।" किंतु लोगों को यकीन नहीं होता। बहस जारी है, जारी है, तरह-तरह की दलीलों और अटकलों का सिलसिला। जब जनता दल के कुछेक महारथी (मसलन देवीलाल, वीपी सिंह आदि) के बंगलोर आने की खबर थी, तब जयललिता का इलाज के बहाने बंगलोर में होना, और भी उत्सुकता का विषय बन गया। कुछेक लाल-बुझक्कड़ों ने जयललिता और रामकृष्ण हेगड़े के बीच राजनीतिक साठगांठ होने तक की बात कह डाली। इसी तरह की बेकरारी और उत्सुकता के साथ कांग्रेसवाले भी अंधकार में तीर मारे जा रहे हैं।

कयास-दर-कयास : काफी तादाद में इंकाई, यह सुराग पाकर कि पार्टी के राज्याध्यक्ष पद से हटाये गये जीके मूपनार राजीव गांधी के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं, खादी का झकझकाता कुर्ता-लुंगी डालकर मद्रास से उड़ चले और दिल्ली पंहुचने लगे। महानगर के मीनाक्षीबक्कम हवाई अड्डे की लानों में भरे मूपनार और उनके उत्तराधिकारी वाजांपदी राममूर्ति के समर्थक एक दूसरे के इर्द-गिर्द चुपचाप चक्कर लगा रहे थे। वाकई, जब मूपनार दिल्ली में तीन दिन रुक गये, तब दिल्ली और मद्रास के बीचवाली तमाम टेलीफोन लाइनें इस हद तक व्यस्त हो गयीं बतायी जाती हैं कि जब भी दिल्ली और मद्रास के बीच संपर्क किया जाता, एक ही जवाब मिलता, "सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया बाद में डायल करें।"

कांग्रेसी इसके बाद भी बदहवास दिखाई देते रहे। खबर फैली कि राजीव गांधी से दो बार बातचीत होने पर भी कोई नतीजा न निकलने पर मूपनार ऊबकर मद्रास लौटे और तत्काल करुणानिधि से संपर्क किया। कहा जाने लगा कि राज्य में टिकट तथा सत्ता के बंटवारे में अगर हाईकमान ने मूपनार को नजरअंदाज किया, तो वे संसदीय चुनावों के पहले ही द्रमुक प्रमुख (करुणानिधि) के साथ चले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं।

उधर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में एनटीआर (रामाराव) को जो सुराग मिला, वह दिल्ली में हाईकमान को मिले सुराग से एकदम भिन्न था। हैदराबाद की चर्चाओं के अनुसार एनटीआर को मद्रास के कुछ दोस्तों ने बताया कि मूपनार, करुणानिधि को कांग्रेस-इ से हाथ मिलाने के लिए राजी करने में लगे हैं, ताकि वे फिर वह ऊंची कुरसी पा जायें जो राममूर्ति ने छीन ली है। कहते हैं, इस खबर से एनटीआर बेहद घबरा उठे। उन्होंने फटाफट करुणानिधि से टेलीफोन पर बात की और वक्तव्य जारी किया, "हम सब राजीव गांधी की कांग्रेस-इ के खिलाफ एकजुट हैं।"

बहुत लोग यह नहीं मानते कि करुणानिधि अपने विकल्पों के बारे में दृढ़ हैं। लेकिन हाल ही केंद्र ने जो रुख दिखाया, उसने उन्हें फिर बिदका दिया है। भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने के मुद्दे पर श्रीलंका से अपनी बातचीत के संदर्भ में नयी दिल्ली ने करुणानिधि को याद तक नहीं किया। इस कारण फिलहाल ऐसी सूरत नहीं बनती कि द्रमुक, राजीव गांधी से खुश हो। फिर भी गठबंधन बदलने की अफवाह गर्म है।

राममूर्ति की विडंबना : तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष वी राममूर्ति द्रमुक से अपनी पार्टी के गठजोड़ की संभावना को दोटूक शब्दों में नकारने में असमर्थ हैं। अन्नाद्रमुक के कट्टरपंथी कहते फिर रहे हैं कि करुणानिधि अब शीघ्र ही राजीव के आगे घुटने टेकनेवाले हैं। जवाब में कहा जा सकता है कि इसके पहले तो उनकी ही नेता (जयललिता) उत्तर के नेता (राजीव) के आगे सर झुका चुकी हैं। लेकिन जो स्पष्ट तथ्य हैं, उन्हें कैसे नकारा जा सकता है? पहली बात तो यह है कि जब बंगलोर की बोम्मई सरकार बरखास्त की गयी, तब करुणानिधि ने इस बात का ध्यान रखा कि राज्य विधानसभा में उक्त विषय पर चर्चा न हो। फिर उन्होंने पूरे मामले पर एक उपेक्षापूर्ण वक्तव्य दे डाला। इसके पूर्व वे विधानसभा में 'परमीशन रिपोर्ट' देने से इनकार कर चुके थे। "क्यों?" यह पूछते हुए प्रसिद्ध राजनीतिक समीक्षक और राजनीतिक पत्रिका 'तुगलक' के संपादक, चो रामस्वामी कहते हैं, "अब भी कांग्रेस और द्रमुक के बीच गठबंधन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कारण, द्रमुकवाले जानते हैं कि उन्हें लोकसभा की तीन या चार से अधिक सीटें मिलनेवाली नहीं हैं और, हालांकि इस वक्त पूरा माहौल उनके माफिक है, चुनाव में करुणानिधि ३३ फीसदी से अधिक वोट हासिल नहीं कर सकते।" चो का ख्याल है कि चुनाव इसी साल अक्तूबर तक होंगे और तब तक कुछ नाटकीय घटना हो सकती है।

इस बीच ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मोरचे, जिसका एक हिस्सेदार द्रमुक भी है, के नेताओं ने आसन्न सत्यानाश को समझ लिया है और यह भी कि करुणानिधि को अब मना-पटा लेने की जरूरत है वरना मामला मोरचा-नेताओं के हाथ से निकल

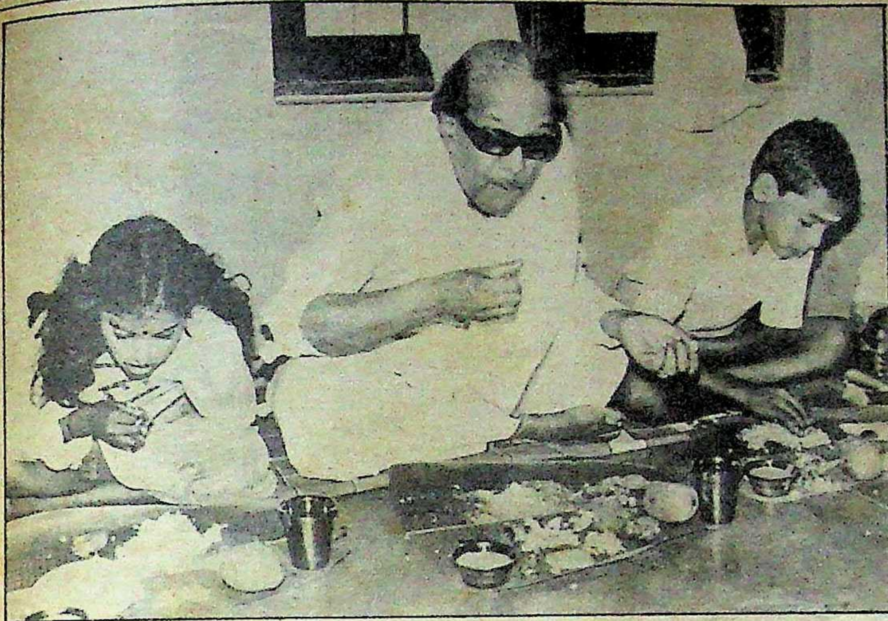

हालात पर नजर : करुणानिधि

> अगर स्थानीय पंडितों की
> बातें मानी जायें, तो मूपनार खुद भी
> 'भीतर से परेशानी पैदा
> करने की अपनी भूमिका' से संतुष्ट हैं।
> यही नहीं, आधे-अधूरे तौर पर
> यह बात भी कही जा रही है कि मूपनार,
> करुणानिधि और
> जयललिता-समर्थक थिरुनवुकारसु की
> तिकड़ी तैयारी के साथ
> सक्रिय हो गयी है,
> ताकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का
> सफाया हो जाये।

जायेगा। यद्यपि, सूत्रों का कहना है, मनाने-पटाने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी है, तथापि राजनीतिक गठजोड़ों को लेकर बात और बिगड़ने की नौबत फिलहाल टल गयी है। इन गतिविधियों की बदौलत करुणानिधि ने न केवल राष्ट्रीय मोरचे के नेताओं के मस्तकों पर चिंता की लकीरें उभार दी हैं, बल्कि तमिलनाडु कांग्रेस-इ के नये नेता वी राममूर्ति के लिए काफी सरदर्द भी पैदा कर रखा है।

स्थानीय सूत्र बताते हैं कि किस कदर राममूर्ति, करुणानिधि और मूपनार के बीच गुपचुप पक रही खिचड़ी से बदहवास हैं। यह गठजोड़ राममूर्ति के लिए उससे भी बड़ी समस्या बन गया है जो उनके विरोधियों ने यह सवाल उठाकर खड़ी की है, "आखिर वे (राममूर्ति) जयललिता के प्रति इतने समर्पित क्यों हैं?" उनकी बदहवासी इतनी बढ़ी बतायी जाती है कि उन्होंने अपने पूर्वाध्यक्ष मूपनार पर नीचा दिखानेवाली टिप्पणी तक ठोंक दी, "उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ वह सहज सुलभ विजय है जो उन्होंने द्रमुक को दिलाने का श्रेय प्राप्त किया।" लेकिन मूपनार और राममूर्ति की बढ़ती जा रही प्रतिद्वंद्विता ही वह सबकुछ नहीं है जो राज्य में कांग्रेस-इ के भविष्य को स्याह बना रही है। जयललिता की डगमग हालत, उनकी वोट-बटोरू काबिलीयत पर बढ़ते संदेह और पार्टी और विधानसभा में मूपनार-समर्थकों की मजबूत स्थिति ने वहम और उलझन का अजीब-सा माहौल खड़ा कर दिया है, जिसमें राममूर्ति फंस गये हैं।

"यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने का वक्त है। अगर मूपनार और उनके आदमी मद्रास तथा दिल्ली के बीच अप-डाउन करते रहे, तो राममूर्ति को भी झख मारकर यही करना होगा। यदि मूपनार कोई ऐसा बयान जारी करते हैं, जिसका लहजा नेता (राममूर्ति) विरोधी हो, तो राममूर्ति भी इसका जवाब देने को विवश हैं। और इस सारी गतिविधियों के साथ ही, दिल्ली से मिले निर्देशों पर अमल भी करना है," यह कहना है उस पत्रकार का जो आजकल तमिलनाडु कांग्रेस-इ की खबरें जुटाने में लगा है। मद्रास को गरमानेवाली दूसरी चर्चा का विषय बूटा सिंह का दौरा है। बताते हैं, इस दौरे में बूटा सिंह, राममूर्ति को कह गये हैं कि वे जयललिता के बहुत करीब न जायें और न शिवाजी गणेशन (जिन्हें राष्ट्रीय मोरचा वाले आजकल लुभा-रिझा रहे हैं) जैसे पुराने कांग्रेसियों से उलझें। एक मूपनार-समर्थक राजनीतिक की टिप्पणी है, "राममूर्ति के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है। विधानसभा में २६ में से २० विधायक अब भी मूपनार की तरफदारी में ही ताल ठोंक रहे हैं। राममूर्ति के साथ जो गिनती के विधायक और रंगराजन कुमार-मंगलम जैसे इक्के-दुक्के केंद्रीय नेता रह गये हैं, तमिलनाडु में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है।"

न इधर के रहे, न उधर के : मूपनार

तिकड़ी का तिकड़म : अगर स्थानीय पंडितों की बातें मानी जायें, तो मूपनार खुद भी 'भीतर से परेशानी पैदा करने की अपनी भूमिका' से संतुष्ट हैं। यही नहीं, आधे-अधूरे तौर पर यह बात भी कही जा रही है कि मूपनार, करुणानिधि और जयललिता-समर्थक थिरुनवुकारसु की तिकड़ी तैयारी के साथ सक्रिय हो गयी है, ताकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो जाये। चो रामस्वामी कहते हैं, "कोई मुद्दा ही नहीं है। एक भ्रष्ट पार्टी दूसरी भ्रष्ट पार्टी से भिड़नेवाली है और जनता का रुख, हर बार की ही तरह, सनकियों जैसा है।"

विचित्र बात यह है कि द्रविण राजनेता कहीं किस्मत आजमाते लगते ही नहीं। कुछ महीनों से गुप्तवासिनी बनी जयललिता अस्वस्थता की आड़ में 'बंगलोर में लुकछिप कर हेगड़े जैसे राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क साधती' बतायी जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में तरजीह न मिलने पर मैडम हेगड़े से हाथ मिला लेंगी। मद्रासवालों की निगाह में अब वे न तो 'वोट बटोरनेवाली' करामाती औरत रह गयी हैं और न 'एमजीआर की विरासत'। "लोग एमजीआर की विरासत को अंगूठा दिखा चुके हैं," यह कहते हैं, आरएम वीरप्पन जो अद्रमुक में कभी जयललिता के साथी थे और अब पार्टी में उनके प्रबल प्रतिद्वंद्वी बन गये हैं। जनवरी में विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद जयललिता और जानकी रामचंद्रन के गुटों का जो विलय हुआ, उसे नामंजूर कर वीरप्पन और उनके कुछेक वफादार साथियों ने हाल ही 'एडीएमके (एमजीआर)' पार्टी बना ली है। वीरप्पन पूछते हैं, "आप कैसे कह सकते हैं कि जयललिता एमजीआर की विरासत की उत्तराधिकारी हैं?" फिर जोर देकर कहते हैं, "हमारी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता नहीं मानेगी जिसे मतदाता और स्वयं एमजीआर भी, खारिज कर चुके हों।"

मनोहर कहानियाँ

जुलाई '८९

प्रमुख आकर्षण

जैना प्रापर्टीज : दिल्ली में घोटाला ही घोटाला

एक जूनियर इंजीनियर के अवैध ढंग से करोड़पति बनने और भवन निर्माण के धन्धे में घपलेबाजी की कहानी

इंदौर का ब्लू फिल्म कांड

मध्य प्रदेश के 'मिनी बम्बई' इंदौर में मार्डलिंग और विज्ञापन एजेंसी की आड़ में ब्लू फिल्मों के निर्माण और अनैतिक धन्धे को उजागर करती हुई कहानी

भारत में हैंगग्लाईडिंग

पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की बिलिंग घाटी में सम्पन्न हुई अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता और भारत में इस रोमांचक खेल के विकास की रोचक कथा

अन्य आकर्षण

- 'एस कुमार्स' के परिवार में विवाद...

उद्योगपति अशोक कासलीवाल द्वारा आत्महत्या के प्रयास से प्रकाश में आयी सम्पत्ति के विवाद की कथा

- एक बेगुनाह बहू की मौत

बम्बई के सम्पन्न परिवार में ब्याही गयी एक सुशिक्षिता युवती के दुर्भाग्य की मर्मस्पर्शी कहानी

- साथ जियेंगे, साथ मरेंगे
- विदर्भ की नन्ही पीटी उषा
- बबिता और सुनील की कहानी
- विचित्र प्रतिशोध

१९ कहानियां और १० लघुकथाएं

कुछ भी हो, विधानसभा चुनाव में जयललिता कामयाब तो रहीं ही, साथ ही और लोगों को यह अहसास कराने में भी कामयाब रहीं कि विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व वे ही संभालेंगी। इस तथ्य की ओर ध्यान खींचने पर वीरप्पन तिरस्कार-भाव के साथ विदूषक की मुद्रा अपना लेते हैं, ''जयललिता सत्ता में रहें, इससे ज्यादा बेहतर उनका विपक्ष का नेता बन जाना ही है। कोई नहीं जानता कि अगले तीन-चार वर्षों में उनकी लोकप्रियता कितनी रह जायेगी और उनके बनाव-सिंगार में कितना आकर्षण बच पायेगा।'' वीरप्पन मानते हैं कि अन्य अधिकांश द्रविड़ नेता करुणानिधि से या जयललिता से जा मिले हैं और इसलिए वे (वीरप्पन) अकेले पड़ गये हैं। उनका ख्याल है कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भी यही अच्छा है कि फिलहाल द्रमुक के साथ 'मित्रवत विपक्ष' के तौर पर काम किया जाये और जब कभी द्रमुक एमजीआर की किसी नीति को लागू करे, उसका समर्थन किया जाये।'' बात यहीं खतम नहीं होती। वीरप्पन आगे कहते हैं, ''हो सकता है कि किसी विचारधारा के तहत हम किसी दल में मिल जायें।'' वीरप्पन आजकल जिस नेता के सबसे करीब जान पड़ते हैं, वे हैं करुणानिधि।

करुणानिधि का कमाल : लेकिन करुणानिधि अपना ही राग अलाप रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पर है कि भिन्न-भिन्न दलों से सौदेबाजी के तरीके भी भिन्न-भिन्न रहें। जानकारीवाले माध्यमों का मानना है कि करुणानिधि को यह रणनीति फिलवक्त खूब रास आ रही है। मद्रास की राजनीति-वाणिज्य-प्रधान पत्रिका 'जूनियर विकटन' ने द्रमुक सांसद वी गोपालस्वामी की गुप्त लंका-यात्रा के अनन्यत्र (एक्सक्ल्यूसिव) छायाचित्र छापकर उनके इस दावे को, कि वे 'तमिल ईलम मुक्ति चीतों' के सर्वोच्च नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन से मिल आये हैं, उचित ठहराया। बाद में ऐसे चित्र अन्य स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में भी काफी छपे। इनमें गोपालस्वामी को प्रभाकरन के साथ भोजन करते दिखाया गया है। इन चित्रों के छपने से स्थानीय पत्रकारों को सोचने-समझने का पर्याप्त मसाला मिला। तब तक वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि श्रीलंका की जटिल स्थिति के बारे में द्रमुक नेता के यकबयक चुप्पी साध लेने का मतलब क्या है?

निष्ठा पर संदेह : राममूर्ति

चूंकि जयललिता की सफलता सीधे एमजीआर के रास्ते पर कदम बढ़ाने और करुणानिधि का विरोध करते रहने से जुड़ी है, इसलिए दिलचस्प बात यह देखना है कि करुणानिधि आगे क्या करते हैं?

इन तस्वीरों की चर्चा चल ही रही थी कि मद्रास की समाचार समितियां तब अचरज में पड़ गयीं, जब खबर मिली कि २५ मार्च को विधानसभा में हुई शर्मनाक वारदात की तस्वीरें अब प्रकाशन-प्रचार के लिए मिल रही हैं। एक सूत्र का कहना है, ''करुणानिधि की इस महाशयता पर आश्चर्य नहीं होता। हैरत में तो यह बात डालती है कि करुणानिधि और उनकी पार्टी के लोग यह समझते थे कि ये तस्वीरें उनकी पार्टी की बदहाली को उजागर करनेवाली हैं।'' किंतु करुणानिधि तो यह कहावत मानते हैं, ''कभी नहीं होने से बेहतर है देर से होना।'' मामला चाहे तस्वीरों का हो या राजनीतिक गठजोड़ों का।

''पार्टी का भविष्य दांव पर लग चुका है। पार्टी की समूची जनशक्ति अपने नेता की अनुगामिनी होती है। इसलिए यदि द्रमुक, कांग्रेस-इ के साथ हो जाये, तो इससे ज्यादा लोग नहीं चौंकेंगे।'' यह निष्कर्ष चो रामस्वामी का है। लेकिन मौजूदा हालात इस दिशा में कोई ठोस संकेत नहीं दे रहे हैं। चूंकि जयललिता की सफलता सीधे एमजीआर के रास्ते पर कदम बढ़ाने और करुणानिधि का विरोध करते रहने से जुड़ी है, इसलिए दिलचस्प बात यह देखना है कि मायावी द्रविड़ नेता (करुणानिधि) आगे क्या करते हैं?

—बालाजी अय्यर, मद्रास से

वीर विक्रमसिंह उर्फ भैया राजा

सामंती आतंक का लोमहर्षक अध्याय

आखिरकार, बुंदेलखंड के इलाकों में आतंक के रूप में कौंधनेवाले कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह को एक हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर ही लिया गया, लेकिन अब वे सारे लोग खौफ के साये में हैं जो वीर विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार समझे जा रहे हैं। खौफ का आलम यह है कि स्टेनगनधारियों से घिरे खुद गृहमंत्री जयपाल सिंह तक सफाई देते घूम रहे हैं कि इस गिरफ्तारी से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। सिर्फ ३९ वर्ष की वय में आतंक का जीवित मिथक बन जानेवाला यह शख्स कौन है, जिसे लोग कमजोरों और गरीबों का रहबर मानते हैं, तो वहीं यह भी जानते हैं कि वह दुश्मनों को अपने पालतू मगरमच्छों और अजगर का आहार बना देता है?

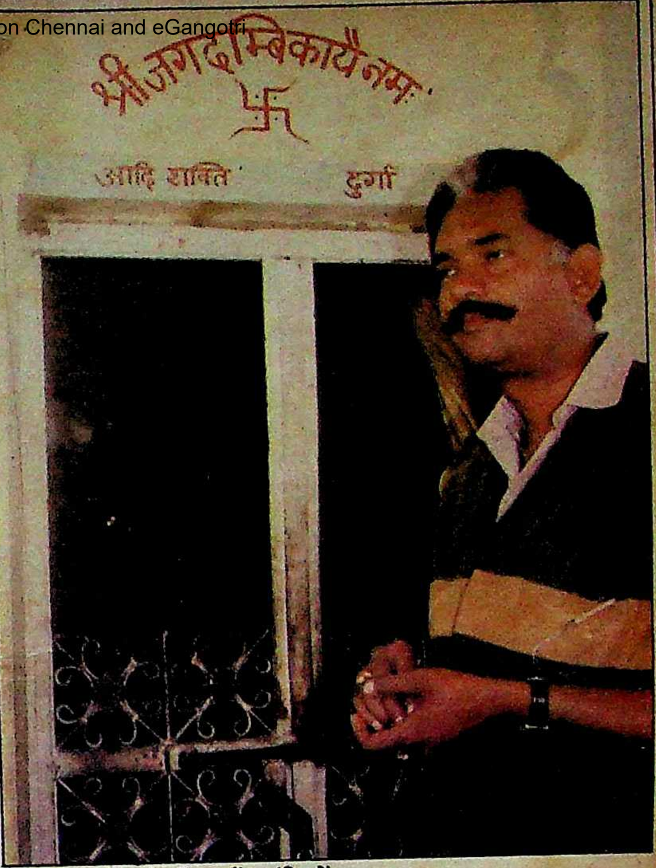

एक रूप यह भी : वीर विक्रम सिंह मंदिर में

बात अविश्वसनीय, लेकिन सच है। बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा इलाका उसके नाम से थर्राता है। इस इलाके में उसका खौफ इतना जबर्दस्त है कि कोई उसके खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता। करीब पांच साल पहले इस व्यक्ति ने पन्ना जिले में पवई निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। चुनाव चिह्न था, हाथी। उसके समर्थकों ने नारा दिया था :

"मुहर लगाओ हाथी पर,
नहीं तो गोली खाओ छाती पर,
और लाश मिलेगी घाटी पर।"

पवई के जर्रे-जर्रे में गूंजे इस नारे ने पवई ही नहीं, आसपास के इलाके को भी गरमा दिया था। चुनाव में मत पाने के लिये उम्मीदवार मतदाताओं की मिन्नतें करते हैं, उन्हें रिझाने के लाख जतन करते हैं। मगर यहां थी, वोट देने, अन्यथा गोली खाने की खुल्लमखुल्ला चेतावनी।

किसी डान या बेताज बादशाह की तरह चुनाव-मैदान में उतरे इस शख्स का नाम है, कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, जिसे समूचे बुंदेलखंड में भैया राजा के नाम से जाना जाता है। पवई से चुनाव में भैया राजा कैप्टेन जयपाल सिंह (वर्तमान गृह एवं परिवहन मंत्री) से मात खा गये, किंतु उन्होंने कैप्टेन को कड़ी टक्कर दी थी। सहानुभूति लहर के बावजूद मिले थोक-बंद वोट इलाके में उसके दबदबे का संकेत थे। चुनाव में पराजय तो हुई, किंतु भैया राजा के साम्राज्य, ऐश्वर्य, दर्प और दबदबे पर कहीं कोई आंच नहीं आयी। उलटे भैया राजा की शानो-शौकत और सामाजिक प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। करीब एक दर्जन छोटे-बड़े पद उनकी झोली में गये, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था, जिला सहकारी बैंक, पन्ना का अध्यक्ष पद। सहकारिता के चुनाव आये, तो वे सहकारिता में अपनी पूरी लाबी की पैठ कराने में सफल रहे। उनके हौसले बुलंद थे। लगा कि आंधी की तरह छा जायेंगे भैया राजा समूचे बुंदेलखंड में। लेकिन तभी नैनीताल जिले में किच्छा में हुए हत्याकांड ने परिदृश्य बदल दिया। २७ मई को भैया राजा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी से अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। क्या 'रासुका' में भैया राजा को बंदी बनाना न्यायोचित है? क्या इस गिरफ्तारी से आतंक का यह मजबूत गढ़ ढह जायेगा? इन प्रश्नों का उत्तर था, पन्ना और छतरपुर में। और उससे बढ़कर छतरपुर जिले के गहरवार ग्राम में।

भैया राजा का साम्राज्य : भोपाल और सागर से छतरपुर के रास्ते पर छतरपुर से छह किमी पहले एक रास्ता तीरांकित दिशा में बायीं ओर मुड़ता है। बारहमासी यह मार्ग ईसानगर को जाता है। ईसानगर से तीन किमी पहले पड़ता है, गहरवार ग्राम। यह गांव भैया राजा के साम्राज्य की धुरी है—एक तरह से उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु और संचालन स्थल।

अधिकांशत: घास-फूस की झोंपड़ियों और मिट्टी की मड़ैयों के इस गांव की आबादी करीब तीन हजार है। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, अहीर, काछी, बसोड़ और आदिवासी समेत सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस गांव में हमें भैया राजा की उस पुश्तैनी गढ़ी में जाने का मौका मिला, जहां कुछ अर्से पहले तक जाने में सरकारी अधिकारी भी घबराते थे। यह गढ़ी गांव में कुछ ऊंचाई पर बनी हुई है। गढ़ी में बिजली है और गांव का इकलौता फोन भी। काफी पुरानी यह गढ़ी कई किमी दूर से दीखती है और यहां के बुर्ज पर चढ़कर बहुत आसानी से आसपास के इलाके और वहां की गतिविधियों को अपनी नजर के दायरे में बांधा जा सकता है।

यह गढ़ी इन दिनों सूनी है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब यहां सामंती वैभव बिखरा पड़ा था। भैया राजा की बेटियां अपनी बुवा के साथ हमें गढ़ी में मिलीं। उन्हें, कुछेक नौकर-चाकरों और स्वामिभक्त पालतू कुत्तों को छोड़ दें, तो गढ़ी भांय-भांय करती नजर आती थी। परिजन और ग्रामीण गढ़ी की श्रीहीन स्थिति के लिए उग्र पुलिस द्वारा बलात् कुर्की और विक्रम सिंह की गिरफ्तारी को

जिम्मेदार मानते हैं। (देखिए बाक्स)

वीर विक्रम सिंह, वस्तुत: बुंदेलखंड में सदियों से काबिज ह्रासग्रस्त सामंती प्रथा का जीवंत प्रतीक है। यह व्यक्ति जीतेजी किंवदंती बन गया है—एक ऐसी किंवदंती, जो केवल गहरवार या पवई मात्र नही, समूचे बुंदेलखंड में, खासतौर पर पन्ना और छतरपुर में आम और खास लोगों की जुबान पर है।

आयु ३६ वर्ष। इकहरा, छह फुटा सुतवां शरीर। सामनेवाले को भेदती हुई पैनी आंखें। बालों में सामने की लट में हलकी सी सफेदी। यह है वीर विक्रम उर्फ भैया राजा का व्यक्तित्व, जिससे ग्रामीणजन ही नहीं, छतरपुर और पन्ना के पुलिस अफसर भी खौफ खाते हैं।

गहरवार वस्तुत: वीर विक्रम का ननिहाल है। उप्र में ललितपुर जिले में कुरा ककरैटी गांव इस परिवार का पैतृक गांव है। छतरपुर के पड़ोसी जिले पन्ना स्थित सांटा बुधसिंह में परिवार की अच्छी खासी चल-अचल संपत्ति है। विक्रम के पिता प्रतिपाल सिंह ने दो विवाह किये थे। वह महाराज विजावर के यहां जागीरदार थे। पहली पत्नी से उत्पन्न इंद्र वीर विक्रम सिंह मप्र पुलिस में आईजी जैसे सम्मानित पद से सेवानिवृत्त होने के बाद टीकमगढ़ में रह रहे हैं। इंद्र वीर विक्रम सिंह और अशोक वीर विक्रम सिंह के अलावा प्रतिपाल सिंह की चार बेटियों के नाम हैं: कांति कुमारी, संतोष राजा, विभा राजा और राजश्री राजा।

आतंक का पर्याय बुंदेलखंड: आतंक के मामले में बुंदेलखंड अभिशप्त है। आतंक यहां सूरज के साथ उगता है, दिन भर परवान चढ़ता है और रात में गाढ़ा हो जाता है। एक ओर जागीरदारों-सामंतों, दूसरी ओर डाकुओं के गिरोहों और तीसरी ओर अफसरों का आतंक। बुंदेलखंड की जनता आज भी यह 'तिहरा आतंक' झेलने को बाध्य है। आज गहरवार, ईसानगर, पवई, मातगवां, किशनगढ़ और देवरा में भैया राजा की तूती बोलती है, तो बसारी रनगवां और खजुराहो में शंकर प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना राजा की। भगवां और बड़ा मलहरा में रामसिंह का दबदबा है, तो चंदला इलाके में सांसद श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी के नाम का डंका बजता है। अपने-अपने इलाके के ये 'बेताज बादशाह' हैं और इनकी मर्जी के बगैर इन इलाकों में पत्ता नहीं हिलता। सामंती आचरण सिर्फ सामंत-पुत्रों की बपौती नहीं है, नव धनाढ्यों और राजनेताओं ने भी यहां पैसे और ताकत के बलपर सामंती रंगढंग और ऐबों को अपनाया है। दुर्दांत दस्युओं और पुलिस अफसरों का यहां यकसां आतंक रहा है। आज भी यहां थाने में 'बुलौवे' पर प्रतिष्ठित नागरिकों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है।

वीर विक्रम ऐसे ही माहौल में पले। एक तरह से वे इसी माहौल की उपज हैं—ताकत की भाषा, ताकत के स्वाद और ताकत की मार से खूब परिचित। गहरवार की गढ़ी उनका सुरक्षा-कवच थी। वे खेती-खलिहानी तक सीमित नहीं रहे। जंगल, मछलियों और तेंदूपत्तों समेत विविध ठेकों से उन्होंने खूब कमाया। किशनगढ़ क्षेत्र में कोई ग्रामीण महुवा, अचार व अन्य वनोपज किसी और को बेचने को सोच नहीं सकता था। कमाई का अनुमान इससे भी लग सकता है कि 'सीजन' में भैया राजा के ठेकों से एक ट्रक मछली रोज लखनऊ जाती थी। ट्रकों से भी उन्हें खासी आय हुई। इलाके में बड़ी संख्या में उन्होंने गांजा, भांग और शराब के ठेके भी लिये।

रंगीनमिजाज भैया राजा, उनके परिचितों के अनुसार, आखेट के बेहद शौकीन हैं। उनके अचूक निशाने का लोहा औरों के साथ-साथ उनके परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भी मानते हैं। शान में गुस्ताखी उन्हें किसी कीमत पर सहन नहीं होती। भैया राजा

राजनीतिक दखल : वीर विक्रम अपनी पत्नी एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशा रानी के साथ

किच्छा हत्याकांड

रहस्यों का जाल

किच्छा में हत्या : सिद्धार्थ राव सांगा

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत वीर विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के सूत्र सीधे उप्र के नैनीताल जिले में, तराई के किच्छा इलाके में, अकबर अहमद डंपी के फार्म पर एक मार्च को हुए हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। इसका यह सिरा रहस्यों में आज भी इसलिए उलझा हुआ है, क्योंकि सेक्स, शराब और अवैध संबंधों की कोख में जन्मे इस हत्याकांड के सभी रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हो सके हैं।

विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से जो कथा बनती है, वह इस प्रकार है: रुद्रपुर के एक संपन्न सिख कृषक का बेटा सिद्धार्थ राव सांगा एक मार्च को सुबह अपने मित्र कृष्णेंद्र दीक्षित के साथ नीले रंग की जिप्सी यूपीपी ५४२ में सवार होकर सात किमी दूर स्थित किच्छा क्षेत्र के लिये रवाना हुआ। किच्छा पहुंचकर वे डंपी के पड़ोसी फार्म पर रुक गये, जो चंद्रकीर्ति सिंह का है। तराई के संपन्न किसानों के बीच प्रचलित रिवाज के मुताबिक चंद्रकीर्ति ने मेहमानों का स्वागत किया और उनसे रात्रि भोज पर रुकने का आग्रह किया, ताकि वह उन्हें मप्र से आये अपने अतिथि से मिला सकें। यह अतिथि और कोई नहीं विक्रम सिंह बताये जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि उस दिन दोपहर एक बजे से ही पीने-पिलाने का दौर शुरू हो गया। तराई में बसे ये आधुनिक सुविधायुक्त आलीशान फार्म अपने आगोश में शानो-शौकत, सेक्स, शराब और अवैध संबंधों की चाशनी में लिपटे अनेक आडंबरपूर्ण रहस्यों को समेटे हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि संपदा अपने साथ ऐब भी लाती है। सिद्धार्थ,

कृष्णेद्र, विक्रम, चंद्रकीर्ति और उसकी पत्नी हर्षिती समेत गिने चुने लोगों की इस बैठक में शिकार के किस्से शुरू हो गये। तीतरों के शिकार से शुरू होकर बात आदमियों के आखेट तक पहुंची। बताते हैं कि सांगा ने राजपूती आनबान और उनकी कुलीनता को लेकर कुछ ऐसी फब्तियां कसीं, जो विक्रम को बुरी तरह चुभ गयीं। उनके जातीय दंभ और सामंती दर्प को आघात पहुंचा।

बहरहाल, सिद्धार्थ एवं कृष्णेंद्र रात को करीब दस बजे जिप्सी से ही फार्म से वहां से रवाना हुए। सूत्रों का कहना है तभी विक्रम ते अपनी बंदूक उठायी, नौकर रामसिंह को साथ लिया और जीप से उनके पीछे रवाना हो गये। सिद्धार्थ ने अचानक डंपी के भाई छोटू के यहां कुछ देर रुकने का निश्चय किया। वहां पहुंचने पर छोटू ने उनसे शराब पीने का आग्रह किया। उन्हें वहां पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी कि रामसिंह को लेकर विक्रम भी वहां पहुंच गये। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सिद्धार्थ और विक्रम में कुछ देर नोंकझोंक हुई और तैश में आकर विक्रम ने गोली दाग दी। गोली लगने से सिद्धार्थ की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। बताते हैं कि गोली कृष्णेंद्र पर भी दागी गयी, किंतु वह बच निकला और उसने आधी रात में थाने पहुंचकर रपट लिखायी।

पुलिस सूत्रों का यहां तक कहना है कि जब सिद्धार्थ की मृत देह कमरे में पड़ी थी, विक्रम ने छोटू से शराब लाने को कहा था। शराब परोसी गयी और भोर में चार बजे तक वे शराब पीते रहे। प्रारंभिक आघात से उबरकर छोटू और उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि वे किसी तरह लाश वहां से हटा दें। इस पर उन्होंने सिद्धार्थ के शव को उसी की जिप्सी में लादा और जिप्सी को शव समेत पास की नदी में धकेल दिया।

इस बीच किच्छा पुलिस ने एक और दो मार्च की मध्यरात्रि में भादंसं के तहत अपराध दर्ज कर लिया था। किच्छा पुलिस विक्रम सिंह पर हाथ डालती, इसके पहले ही वे आननफानन वहां से रवाना होकर छतरपुर स्थित अपनी गढ़ी में लौट आये।

'माया' को उपलब्ध जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह मप्र के एक राजघराने की रूपसी महिला के न्यौते पर किच्छा गये थे। इस महिला को विश्वास था कि उसकी संपत्ति के विवाद को सुलझाने में विक्रम सहायक सिद्ध होंगे। घटनाक्रम बताता है कि यह उलझन तो नहीं सुलझी, मगर विक्रम सिंह पेचीदा संकट में फंस गये, जिसका परिणाम अंततोगत्वा 'रासुका' के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी में हुआ। वैसे यह बात मायने रखती है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस-विज्ञप्ति जारी हुई और जो आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें पृथक से और स्पष्ट शब्दों में किच्छा कांड का कहीं उल्लेख नहीं है।

—सुधीर

के बारे में अधिकांश किंवदंतियां उनकी इन्हीं आदतों से जुड़ी हुई हैं।

बताया जाता है कि मई में जब उप्र पुलिस परवाना लेकर गहरवार आयी थी, तो गढ़ी में पालतू मगरमच्छ देखकर भौंचक रह गयी थी। पुलिस के आने के कुछ दिनों बाद इन मगरमच्छों को यहां से हटा दिया गया, किंतु ये किंवदंतियां आज भी जीवित हैं कि इन मगरमच्छों को मानुष-मांस यानी जिंदा आदमी के गोश्त पर पाला गया था। किंवदंतियों में अक्सर अतिशयोक्ति का पुट रहता है। मजे की बात है कि इन अतिरंजित कथाओं को पुलिस ने भी हवा दी है। उनका कहना है कि भैया राजा के हाथों बहुतेरे लोग इन मगरों के ग्रास बने। मगरों की भांति वीर विक्रम ने अजदहा व कुछ अन्य वन्यप्राणी भी पाल रखे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि अजदहे से वे न केवल ग्रामीणों को डराते थे, वरन् उन नवयौवनाओं को उससे डसाने का भी खौफ दिलाते थे, जो उनकी अंकशायिनी होने से इनकार करती थीं। आज के जमाने में ये बातें अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दैनिक ने यहां तक लिखा है कि बुंदेलखंड के एक सौ किमी के इलाके में यह धारणा प्रचलित है कि इस क्षेत्र में जो भी नयी दुल्हन ब्याह कर आयेगी, उसे पहली रात भैया राजा के साथ गुजारनी होगी। एक अंग्रेजी नियतकालिक ने पुलिस के हवाले से तीन सौ से ज्यादा लोगों के मगरमच्छों का आहार बनने की बात इस अंदाज में लिखी, जैसे उसे यह खबर देनेवाला पुलिसकर्मी मगरमच्छों के सामने निवाले के तौर पर फेंके गये लोगों की गिनती करने की ड्यूटी पर ही तैनात था।

जिन परिस्थितियों में किच्छा में हत्या हुई: अकबर अहमद डम्पी का फार्म हाउस

आरोप एक दो नहीं: छतरपुर के पुलिस अधीक्षक एसके पासवान के अनुसार, वीर विक्रम पर अदालतों में २१ मामले चल रहे हैं और ईसानगर थाने में १९८२ से उसका नाम निगरानीशुदा बदमाशों की लिस्ट में है। उस पर कानून को खिलौना बनाकर खेलने का भी आरोप है। १९८७ में उसने छतरपुर के उप पुलिस अधीक्षक आरसी पाठक की पिटाई कर दी थी। ईसानगर के थाना प्रभारी एनडी खरे ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की, तो उसे मुकदमे में फंसा दिया गया। ऐसे ही उसने ईसानगर के हेड-कांस्टेबल को प्रताड़ित किया और आरक्षक गुलाब सिंह को बस स्टैंड पर मारा। युवा अभिभाषक निहाल सिद्दीकी के पांवों पर इसलिए गोली मार दी गयी, क्योंकि उसने भरी सभा में भैया राजा के अत्याचारों की कथा सुना दी थी। एक सरकारी अधिकारी ने विक्रम के सामंती रंगढंग की मिसाल यह कहकर दी कि वह घोड़े से उतरते समय पांव रकाब से निकाल कर सीधे जमीन पर न रखकर आदमी की पीठ पर रखने का शौकीन है।

पुलिस रिकार्ड के अनुसार, विक्रम के खिलाफ पहला मामला सन् ७० में ईसानगर थाने में दर्ज हुआ था। उन पर आरोप लगा था कि वे आपराधिक आशय से भयानक आयुध लेकर पराये घर में घुसे, महिला की बेइज्जती की और अपहरण एवं जान से मारने की धमकी दी। उनके खिलाफ समय-समय पर थाना सिविल लाइंस एवं कोतवाली छतरपुर, ईसानगर, गहराजपुर, किशनगंज, बुडरा थानों में अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, हत्या की धमकी, शासकीय कर्मचारियों से मारपीट, डकैतों को संरक्षण, डकैती का माल लेने, चोरी, अपहरण, आगजनी आदि के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए। इनमें आधे से अधिक प्रकरण गवाहों के पक्षद्रोही होने या साक्ष्य न मिलने के कारण खत्म हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में विक्रम की फाइल में विक्रम के खिलाफ सतना, पन्ना और टीकमगढ़ में भी मामले दर्ज होने की संभावना का उल्लेख है। उन पर सबसे गंभीर

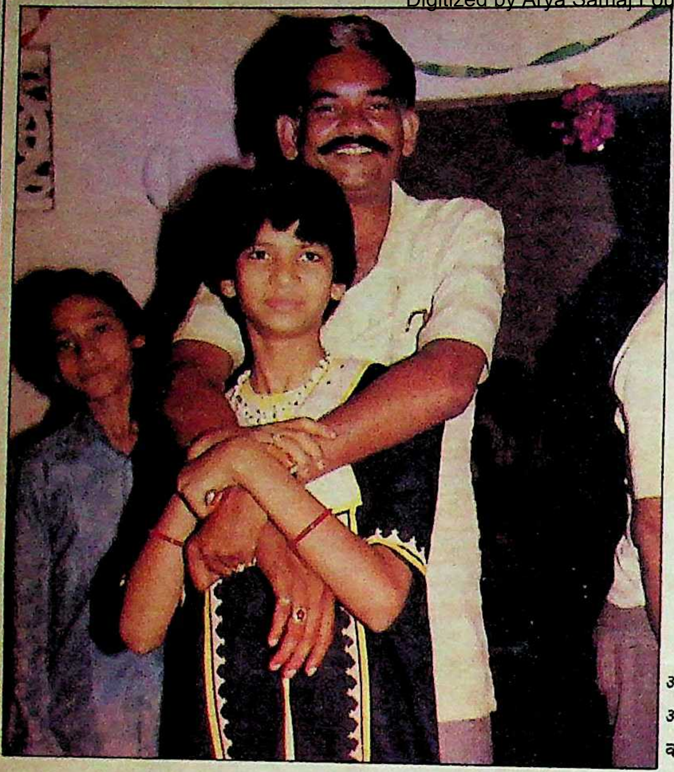

आतंक दूसरों के लिए: अपनी बेटी के साथ वीर विक्रम सिंह

आरोप यह है कि उन्होंने चार्ली राजा और सूरज लोधी के दुर्दांत दस्यु गिरोहों को प्रश्रय दिया। पुलिस एवं उनके विरोधियों का कहना है कि हत्या, हत्या की धमकी, बलात्कार और जमीन पर जबरिया कब्जे के बहुत से मामले इस कारण दर्ज नहीं हुए, क्योंकि प्रताड़ित लोगों में आतंक के कारण जुबान खोलने का साहस नहीं था।

फरियाद: ग्राम गहरवार के श्रीप्रसाद दुबे ने ८ जुलाई '८८ को प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वीर विक्रम का कच्चा-चिट्ठा भेजा और कार्रवाई की मांग की। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, गृहमत्री, क्षेत्रीय सांसद, डीजीपी, कलेक्टर एवं एसपी आदि को भेजी गयी। अपने शिकायतनामे में दुबे ने लिखा कि उसकी गांव गहरवार में २५० एकड़ भूमि है, किंतु वह भैया राजा के आतंक के कारण दो साल से गांव में खेती नहीं कर पा रहा है। आतंक व फर्जी मुकदमों के कारण वे लोग गांव छोड़ने को बाध्य हो गये हैं। गांव में अकेला उसी का परिवार आतंक के खिलाफ उंगली व आवाज उठाता है, इसलिए उसका जीना मुहाल कर दिया गया है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि भैया राजा से गृहमंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह भी डरते हैं। यदि यही स्थिति रही, तो पूरे छतरपुर-पन्ना में कांग्रेस का नाम नहीं बचेगा।

भोपाल और दिल्ली के आला अफसरों और नेताओं को इसी तरह की शिकायतें और भी कुछ लोगों ने भेजी हैं। भैया राजा की बहन राजश्री राजा से इस बारे में पूछने पर उन्होंने इन बातों को निराधार ठहराया। राजश्री के अनुसार, गांव में बरसों श्रीप्रसाद दुबे के परिवार की सूदखोरी का आतंक रहा। १९६५ में जब विक्रम स्कूली छात्र थे, तब एक दिन आवेश में आकर उन्होंने दुबे के सारे बहीखाते छीनकर जला दिये थे। इससे वे गांव में 'हीरो' हो गये और दुबे परिवार उनका जानी दुश्मन। राजश्री के शब्दों में, "गांव में गढ़ी को भय नहीं सम्मान से देखा जाता है। यह इसी का परिणाम है कि गांव में सारे काम मिलजुलकर होते हैं। गढ़ी में कोई काम होने पर पूरा गांव आ जुटता है। भैया राजा को लोग इस नाते मानते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव में चांपाकल लगवाये, बहुतों को खेती किसानी के लिए पैसा दिया और कइयों का कन्यादान किया।" बातचीत के दौरान राजश्री राजा ने १९७३ की भी एक घटना बतायी। तब विक्रम को एक सांप ने काट लिया था। विक्रम के सांप के काटने पर अचेत होने से सारे गांव में हायतौबा मच गयी थी। हर घर में पूजापाठ, मनौती और अर्चना की गयी थी, तब कहीं जाकर विक्रम के प्राण बचे थे।

राजनीति का पहलू: मप्र शासन में गृह एवं परिवहन मंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह को भैया राजा का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। दोनों के बीच छत्तीस का रिश्ता बताया जाता है। वीर विक्रम ने सन् ८५ में कैप्टेन के खिलाफ पवई से चुनाव लड़कर इस रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। अर्जुन सिंह के पिछले ११ माह के मुख्यमंत्रित्वकाल को छोड़ दें, तो कैप्टेन बरसों से मंत्री हैं। बुंदेलखंड की राजनीति में कैप्टेन सिंधिया-वोरा के हितों के प्रतीक हैं, तो भैया राजा इस दशक के शुरू से ही अर्जुन सिंह के खास आदमी हैं। गत वर्ष गर्मियों में सहकारी बैंक, पन्ना के कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह शरीक हुए थे। इसके पूर्व अप्रैल, १९८८ में कैप्टेन ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पत्र लिखा था कि चूंकि वीर विक्रम कांग्रेस-इ से निष्कासित और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अतः मुख्यमंत्री का उसके कार्यक्रम में जाना उचित नहीं होगा। कैप्टेन ने अपना मौखिक विरोध अर्जुन सिंह से भी व्यक्त किया था, किंतु अर्जुन सिंह पन्ना गये और उन्होंने बैंक के भवन के उद्घाटन समारोह में विधिवत भाग लिया।

दोनों पक्षों को तौलें, तो भैया राजा कहीं से कमजोर नजर नहीं आते। उनके पास दौलत है और ताकत भी। उनकी पत्नी श्रीमती आशारानी गहरवार की महिला पंचायत सरपंच और ईसानगर जनपद की अध्यक्ष हैं। भैया राजा के ससुर जुझार सिंह बिजावर से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित विधायक हैं। भैया राजा के सहयोगियों का कहना है कि कैप्टेन के कारण ही भैया राजा की 'मीसा' के तहत गिरफ्तारी हुई है, जबकि कैप्टेन इससे इनकार करते हैं। स्वयं भैया राजा का कहना है कि कैप्टेन और कुछेक नेतागण छतरपुर-पन्ना में उनकी लोकप्रियता व पैठ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। 'माया' से बातचीत में वीर विक्रम ने कहा, "अभी हाल में प्रारंभ हुए सहकारी क्षेत्र के चुनावों में इन लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिला थोक उपभोक्ता भंडार, पन्ना में अध्यक्ष पद पर मेरे साथी राधिका प्रसाद तिवारी चुने गये। इसी प्रकार जवाहर विपणन सहकारी समिति, देवेंद्रनगर, पन्ना के अध्यक्ष पद पर मेरे साथी वेदनारायण चंदपुरिया चुने गये। वीरसिंह यादव बिजावर विपणन समिति के अध्यक्ष हुए हैं, जिस पर छतरपुर के सभी लोगों की निगाहें थीं। अब केंद्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंकों के चुनाव जो सहकारिता के आधार हैं, शीघ्र होनेवाले हैं। मैं चुनाव में खड़ा न हो सकूं या सक्रिय भागीदारी न रखूं इसी उद्देश्य से यह ओछी राजनीति का घृणित षड्यंत्र रचा गया है।"

राजा भैया की गिरफ्तारी: मप्र शासन के अधिकारी भैया राजा की आपराधिक पृष्ठभूमि को 'रासुका' में उन्हें बंदी बनाये जाने का सबब मानते हैं। मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किच्छा कांड ने उनकी गिरफ्तारी में सर्वप्रमुख भूमिका निभायी है। किच्छा कांड के सिलसिले में भैया राजा को तलाश करती हुई उप्र पुलिस अप्रैल में छतरपुर आयी और गहरवार में उसकी मांद तक जा पहुंची, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। उप्र पुलिस की यह शिकायत भी रही कि मप्र पुलिस ने उसके साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया। गहरवार आने के बाद ही उप्र पुलिस को भैया राजा के असली रुतबे और ताकत का पता चला। गढ़ी में मगरमच्छ और ग्रामीणों का पुलिस से पूर्ण असहयोग उनके लिये अप्रत्याशित था। इसके बाद नये सिरे से वीर

साक्षात्कार :

अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा

मुझे बलि का बकरा बनाया गया है

माया : *माना जाता है कि आपको किच्छा कांड में लिप्त होने के कारण 'रासुका' के तहत बंदी बनाया गया। आपका किच्छा कांड में हाथ है या आपको इसमें किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया?*

भैया राजा : किच्छा कांड एक बहुप्रतीक्षित और उच्च राजनीतिक षड्यंत्र का सुनियोजित परिणाम है। मैं सो रहा था, मुझे तो सुबह पता चला। ऐसा सुना जाता है कि मृतक सिद्धार्थ के पिता श्री राव जो कि इंजीनियर थे, की हत्या करा दी गयी थी। उस समय सिद्धार्थ बच्चा था। बाद में सांगा ने मृतक की मां से विवाह कर लिया एवं उसकी संपत्ति का स्वामी बन गया। बड़ा होने पर मृतक (सिद्धार्थ) अपनी मां एवं पिता की पृथक संपत्ति का उपभोग अपनी इच्छानुसार करना चाहता था, जबकि सांगा ऐसा नहीं चाहते थे। मृतक के मित्र उसे मजाक ही मज़ाक में पुरानी बातों की याद दिलाकर चिढ़ाते थे। इस विषय ने एक-दो बार उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे सांगा स्वयं अपने सौतेले पुत्र से सशंकित थे। मेनका गांधी की ट्रकों को लेकर डंपी ब्रदर्स एवं सांगा के आदमियों में लड़ाई भी चल रही थी। इस विषय में छोटू (डंपी का भाई) के विरुद्ध एक सरदार की मारपीट का मुकदमा भी किच्छा में चल रहा है। मृतक की नानी के नैनीतालवाले मकान को लेकर भी मृतक एवं छोटू खान में तनाव था, क्योंकि उस पर छोटू का कब्जा था। अभी मुकदमा लंबित होने के कारण इस विषय में अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। मुझे तो इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है।

माया : *क्या आपकी गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में किसी तरह का राजनीतिक दबाव है?*

भैया राजा : मुझे मानसिक कष्ट पहुंचाने एवं राजनीतिक दबाव के उद्देश्य से ही यह कार्रवाई की गयी है। वे चाहते हैं कि इससे मेरे राजनीतिक सहयोगी भयभीत होकर या तो मेरा साथ छोड़ दें या फिर निष्क्रिय हो जायें। मुझ पर 'मीसा' लगाना हास्यास्पद कार्रवाई है। मुझे राज्य शासन ने २० सूत्री समिति का सदस्य तमाम जांचों के बाद ही तो बनाया होगा? मैं एक दर्जन से अधिक पदों पर हूं। यह विशुद्ध राजनीतिक-मानसिक दबाव की प्रक्रिया है।

माया : इसमें कहां तक सचाई है कि कैप्टेन जयपाल सिंह और कुछ नेताओं ने द्वेषवश यह कार्रवाई करायी है?

भैया राजा : कैप्टेन जयपाल सिंह मेरे राजनीतिक वर्चस्व को सह नहीं पा रहे हैं, अतः पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सारी कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से द्वेषवश कैप्टेन जयपाल सिंह द्वारा की गयी है।

माया : *कहा जाता है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आपका छतरपुर, पन्ना के इलाके में खासा आतंक व दबदबा है?*

भैया राजा : यदि मैं अपराधी हूं, तो न्यायालय मुझे अवश्य दंडित करता, जोकि नहीं किया। 'एनएसए' की चार्जशीट में वे मामले दर्शाये गये हैं, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। प्रारंभ से सूचना एवं प्रसारण विभाग जयपाल सिंह के अधीन रहने से उन्हें मेरे विरुद्ध छोटे अखबारों में प्रचार करने की सुविधा रही है। मेरी लोकप्रियता या आतंक के विषय में दोनों जिलों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ही जानकारी लेना उचित होगा।

माया : *सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर आपको रींवा से बाहर न ले जाने का निर्देश दिया था, किंतु गिरफ्तार करके रायपुर ले जाया गया। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?*

भैया राजा : मैं असाध्य रोग से पीड़ित हूं। जिस कारण चल फिर भी नहीं सकता। ऐसी अवस्था में भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस ने तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए मुझे जबरन स्ट्रेचर पर डालकर, पुलिस वाहन में लादकर रायपुर भेज दिया, जबकि छतरपुर में भी जिला जेल है। जिला प्रशासन ने छतरपुर जेल में ही रखे जाने की याचिका मेरी जनपद अध्यक्ष पत्नी के मुंह पर फेंक दी एवं स्पष्ट तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। डीएसपी छतरपुर इच्छाराम भटेले ने कहा कि ऐसे आदेश हम जूतों के फीतों में बांधे रहते हैं। मुझे रायपुर भेजना जिला प्रशासन एवं पुलिस का तानाशाही रवैया दर्शाता है। जब मुझे भेजा जा रहा था, तब मैं किसी भी रूप में यात्रा के लिए सक्षम नहीं था।

माया : इसमें कहां तक सचाई है कि आप पर कार्रवाई के पीछे आपको चुनाव में भाग लेने से रोकने का मंशा काम कर रहा है?

भैया राजा : सहकारिता के क्षेत्र में दोनों जिलों में मेरा पूर्ण वर्चस्व है। उपभोक्ता भंडार एवं विपणन सहकारी समितियों के चुनाव में मेरे लोग अभूतपूर्व बहुमत से जीते हैं। मेरा विश्वास है कि कभी न कभी उच्च नेता मेरी व्यथा को सुने-समझेंगे एवं मेरे जनाधार का मूल्यांकन करेंगे। मैं इसी आशा पर संगठनात्मक कार्य, जनता एवं देश की सेवा करता रहूंगा। परंतु यदि उच्च नेताओं ने कैप्टेन जयपाल सिंह जैसे नेताओं की सामंतशाही पर रोक नहीं लगायी, तो कांग्रेस-इ का जनाधार क्या होगा, स्पष्ट है? बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी मनमानी का खमियाजा कांग्रेस को सन् ८५ में भुगतना पड़ा था, जिसे अर्जुनसिंह एवं मोतीलाल वोरा स्वयं भलीभांति जानते हैं।

माया : फिलहाल आप 'रासुका' में बंदी हैं। ऐसे में आप चुनाव कैसे लड़ेंगे?

भैया राजा : हर हालत में मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। मुझे कहीं भी रखें, ईश्वर की कृपा और अपने राजनीतिक सहयोगियों के कारण मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा।

—सुधीर सक्सेना

विक्रम पर हाथ डालने की कोशिशें शुरू हुईं। इस बीच वीर विक्रम चौकन्ना हो गये थे। उन्होंने मगरमच्छों को अन्यत्र भेज दिया और बताते हैं कि कीमती सामान भी गढ़ी से हटा दिया।

सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार, भैया राजा की कोशिश थी कि जैसे भी बने उप्र पुलिस के हाथ पड़ने से बचा जाये। इस फेर में उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। वीर विक्रम सिंह और रामसिंह ने ३ मई को हाईकोर्ट में अर्जी लगायी कि उन्हें किच्छा में अपराध क्रमांक ६७ धारा ३०२/३४ में जमानत और अदालत द्वारा नियत तिथि पर नैनीताल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश प्रदान किया जाये। इस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश रामपालसिंह ने ६ मई को निर्देश दिया कि आवेदकगण किच्छा थाने में आत्मसमर्पण कर सकते हैं अथवा उप्र के न्यायालय से 'रिलीफ' प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जहां तक मप्र. में उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, पुलिस उन्हें ३१ जुलाई १९८९ तक गिरफ्तार न करे।

अशोक वीर विक्रम सिंह ने बचाव के लिये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश एमएच कानिया ने आदेश सुनाया कि जब तक आवेदक स्वास्थ्य के आधार पर रींवा से बाहर ले जाने की स्थिति में नहीं है, उसे नैनीताल ले जाने की कोई कार्रवाई न की जाये। न्यायालय ने इससे सहमति व्यक्त की कि तब तक वह सीजेएम, रींवा की 'कस्टडी' में रहे।

इस बीच शासकीय स्तर पर भी घटनाक्रम

राजनेता या माफिया ? : वीर विक्रम और अर्जुन सिंह

की सुई बहुत तेजी से घूम रही थी। १२ मई को छतरपुर के पुलिस अधीक्षक एसके पासवान ने जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) जेएन पांडेय को रपट भेजकर अशोक वीर विक्रम को 'रासुका' के तहत बंदी बनाने की मांग की। जिला दंडाधिकारी के यहां यह प्रतिवेदन करीब दो हफ्ते लंबित रहा। अंततः २७ मई को जब भैया राजा अपनी गढ़ी में निश्चिंत बैठे थे, तब पुलिस ने उन्हें 'रासुका' के तहत गिरफ्तार कर लिया।

विरोध की कैफियत : 'रासुका' के तहत भैया राजा की गिरफ्तारी कुछ लोगों को नागवार गुजरी, तो बुंदेलखंड के कुछ राजनेताओं को इससे भीतर ही भीतर हार्दिक प्रसन्नता भी हुई। विरोधस्वरूप एक दिन ईसानगर बंद भी रहा। 'माया' से चर्चा में अनेक लोगों ने कहा कि यह सब कांग्रेस-इ के आंतरिक विग्रह का परिणाम है। गिरफ्तारी के विरोध में सबसे खुलकर बोले, बिजावर के भाजपा विधायक जुझार सिंह। जुझार सिंह ने 'माया' से कहा, "भैया राजा को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वितावश बंद किया गया है। गत चुनाव में उसने कैप्टेन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वह लोकप्रिय है, जनता उसे चाहती है, अतः कैप्टेन को खतरा है कि उसके चुनाव लड़ने पर वे हार न जायें।" बात जब दामाद के आतंक के बारे में चली, तो जुझार सिंह ने कहा, "कैप्टेन ने दंडाधिकारियों पर दबाव डालकर यह गिरफ्तारी करायी है। गहरवार मेरे बिजावर क्षेत्र में आता है। मुझे उसके आतंक या धौंस की आज तक कोई शिकायत नहीं मिली।"

'माया' ने इस बारे में राज्य के गृहमंत्री से संपर्क साधा, तो उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डालने या अपना हाथ होने से सर्वथा इनकार किया। कार्रवाई को प्रावधानों के अंतर्गत बताते हुए कैप्टेन ने कहा, "मुझे इसका पता गिरफ्तारी के बाद तब लगा, जब प्रकरण राज्य शासन के पास अनुमोदन के लिए आया।"

अनेक लोग मानते हैं कि सहकारी बैंक, पन्ना के अध्यक्ष पद समेत कई सम्मानित पदों पर आसीन एक कांग्रेसी नेता की 'रासुका' के तहत गिरफ्तारी अप्रिय व अवांछित घटना है। ऐसे लोगों का कहना है कि चुनावी वर्ष में यह घटना दूर तक असर डालेगी। इस बारे में भी गृहमंत्री समेत कई नेताओं से 'माया' की बात हुई। छतरपुर के कांग्रेसी नेताओं ने तो भिन्न-भिन्न कारणों से इस संबंध में चुप्पी साधी, किंतु गृहमंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार तो भैया राजा को छह सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। लिहाजा वह कांग्रेसी हैं ही नहीं।" वीर विक्रम को पार्टी से निकाला इसलिए गया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस-इ के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और कोई नहीं कैप्टेन जयपाल सिंह थे।

गिरफ्तारी का विरोध : भाजपा विधायक जुझार सिंह

गहरवार का यथार्थ

भोपाल से रवाना होकर हम लोग जब गहरवार पहुंचे, तो सांझ ढल रही थी। अचानक गांव से दो-तीन किमी पहले गाड़ी में कुछ खराबी आ गयी। जहां गाड़ी बिगड़ी वहां से अस्ताचलगामी सूर्य की रोशनी में गढ़ी को देखा जा सकता था। इस गढ़ी में पाले गये मगरमच्छों, अजदहे और वहां विद्यमान काल कोठरी को लेकर तरह-तरह की कथाएं इलाके में प्रचलित हैं।

इसी गढ़ी में भैया राजा की बेटियों और बहन राजश्री राजा से हमारी मुलाकात हुई। राजश्री, बेटियों, ग्रामीणों और गांव के चौकीदार नत्थू—सभी ने एक स्वर से उत्तर प्रदेश पुलिस के भैया राजा के साथ निर्मम सलूक की शिकायत की। राजश्री ने कहा, "भैया को फंसाया गया है। इलेक्शन का चक्कर है। एक बार वे कैप्टेन जयपाल सिंह के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। गरीबों में बहुत पापुलर हैं।" बात आतंक की चली, तो उन्होंने कहा, "आप गांव में घूम लीजिये। आपको अंदाज हो जायेगा कि उनका कितना आतंक है?"

इसे भय मिश्रित श्रद्धा कहें या बरसों के आतंक को नियति मान लेने का प्रतिफल कि गहरवार में एक भी मुख से भैया राजा के खिलाफ शिकायत या अपशब्द सुनने को नहीं मिला। अध्यापक भैरोप्रसाद खरे और बिहारीलाल ने कहा, "हम तो भैया राजा को ही विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मानते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारी मांगें पूरी होती हैं।" हतनारी गांव के हरजिन श्रमिकों—बच्चा, कामता, बब्बू और नत्थू से रास्ते में मुलाकात और बात हुई, तो उन्होंने भैया राजा को सराहते हुए कहा, "उन्होंने गल्ला में गल्ला दिया, पानी में पानी। उनकी छांव तले हमें कभी तकलीफ नहीं हुई।"

गहरवार की कई औरतों से भी बातें हुईं। हाथ भर के घूंघट में बालिश्त भर की ओट किये उन्होंने जो दुखड़ा रोया, वह अचरज पैदा करता है और भैया राजा की प्रचारित आतंकवादी सामंत की छवि से मेल नहीं खाता। नवयुवती सुंदर ने कहा, "हमें न धन चाहिए न पैसा, हमें तो 'मालक' चाहिए।" हमारे प्रयोजन से अनभिज्ञ औरतों और मर्दों ने हमारे पैरों में गिरते हुए कहा, "बगैर दाऊ हमारी दशा बिन पंखों के पखेरू जैसी है।" गांव में तैनात पुलिस गारद की अभद्रता व प्रताड़ना की शिकायत भी कई लोगों ने की।

—सुधीर

कारागार से धमकी : अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा फिलहाल रायपुर कारागार में हैं। उनका मंशा आगामी चुनाव लड़ने का है। उनकी चली तो वे पवई से एक बार फिर कैप्टेन जयपाल सिंह को चुनौती देना चाहेंगे। उनकी पत्नी श्रीमती आशारानी भी बिजावर या कहीं और से चुनाव लड़ सकती हैं। वे कांग्रेस-इ के टिकट की दावेदार भी हैं। भैया राजा पुलिस कैद से किसी प्रकार बाहर आना चाहते थे, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके। रायपुर में डीके अस्पताल में पुलिस के कड़े पहरे में डाक्टरों ने चार घंटे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें वापस जेल के सीखचों में भेज दिया गया। इस बीच छतरपुर में कलेक्टर और एसपी के आवास पर स्टेनगनधारी पुलिस तैनात कर दी गयी है और उनकी कारों के आगे-पीछे सशस्त्र सुरक्षा बल की गाड़ियां चलती हैं। कड़े सुरक्षा प्रबंध की वजह यह बतायी जाती है कि भैया राजा ने रायपुर जेल से उन्हें जान से मारने की धमकी भेजी है।

भैया राजा जेल में कब तक रहेंगे? किच्छा कांड (देखें बाक्स) में उनके साथ क्या सलूक होगा? क्या उनका चुनाव लड़ने का मंशा पूरा होगा? ये सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। किंतु एक बात आज की तारीख में कही जा सकती है कि यह असमाप्त प्रसंग बुंदेलखंड में आगामी चुनाव-लहर को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करेगा।

—सुधीर सक्सेना, छतरपुर से

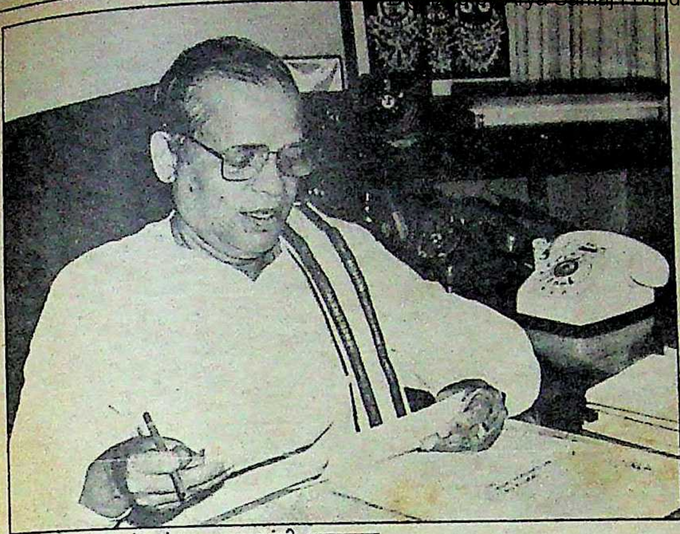

नाज 'कुशल प्रबंधन' पर: मुख्यमंत्री पटनायक

कैसे काटे जानकीबल्लभ पटनायक ने अपने नौ साल ?

वैसे तो कांग्रेसशासित प्रांत के मुख्यमंत्रियों की कुरसी बराबर हिलती रहती है, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक में ऐसी कौन सी खासियत है कि वे विगत नौ वर्षों से मुख्यमंत्री की कुरसी पर जमे बैठे हैं ?

मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक को क्या पता था कि उन्हीं के विधानसभाई क्षेत्र अथगढ़ में १२ जून को आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट की फील्ड उनके विरुद्ध विक्षुब्ध नेताओं की रणस्थली बन जायेगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। इस टूर्नामेंट में असंतुष्ट नेता और पूर्वमंत्री वसंत बिस्वाल को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। वसंत के साथ इस कार्यक्रम में पटनायक से क्षुब्ध विधायकों की एक छोटी-सी टुकड़ी भी आयी हुई थी जिसमें रसानंद साहु, डी प्रधान तथा अमर प्रधान उल्लेखनीय थे। टूर्नामेंट जब समाप्त हुआ, तो वही भीड़ एक सभा में तब्दील हो गयी। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री पटनायक की बेतहाशा खिंचाई की और कहा कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री इतने वर्षों से कर रहे हैं, आज वह क्षेत्र विकास का मोहताज क्यों है ? चौद्वार से इंका विधायक रसानंद साहु काफी उत्तेजित थे इसीलिए उन्होंने मुनादी की कि अगला विधानसभाई चुनाव वे इसी क्षेत्र से लड़ेंगे। साहु ने कहा कि अगर कांग्रेस ने पटनायक को यहां से टिकट दिया, तो वे निर्दलीय लड़ेंगे और इस क्षेत्र की खोयी हुई अस्मिता की बहाली फिर से करेंगे जो पटनायक की वजह से नष्ट हुई है। दरअसल, अथगढ़ क्षेत्र के मूल निवासी रसानंद साहु पहले अथगढ़ से ही विधायक हुआ करते थे। पर १९८० में जब जानकी बल्लभ पटनायक उडीसा की राजगद्दी पर बैठे, तो पटनायक को विधान सभा का चुनाव लड़ना पड़ा। उस समय चूंकि रसानंद साहु के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्होंने पटनायक के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। १९८५ के चुनाव में भी पटनायक इसी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और रसानंद को अपने गृह-क्षेत्र के बजाय चौद्वार से चुनाव लड़कर संतोष करना पड़ा था।

सत्ता का जश्न: ९ जून को पटनायक अपनी सुदीर्घ सत्ता के नौ साल पूरे होने का उत्सव मनाकर साबित कर चुके थे कि चाहे जितनी भी तीखी विक्षुब्ध गतिविधियां हों या भ्रष्टाचार के कितने ही सघन आरोप हों, सब बेमानी हैं। सत्ता के परम रहस्य के वे ज्ञाता हैं, इसलिए श्रीमती गांधी के जमाने से लेकर राजीव-राज, तक वे अविचल हैं। लगातार नौ साल तक कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में पटनायक ने गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराने की योग्यता हासिल कर ली है। ९ जून को सत्ता के नौ साल पूरे होने पर जब उड़िया अखबारों ने पटनायक से उनकी सफलता का रहस्य पूछा, तो पटनायक ने उपदेशात्मक लहजे में कहा—"राजनीति में कुशल मानव प्रबंध की आवश्यकता होती है।" उड़ीसा से लेकर दिल्ली दरबार तक 'कुशल प्रबंधन' के दम पर ही पटनायक की सत्ता दीर्घजीवी है। पिछले महीनों में राजीव गांधी ने उड़ीसा की बार-बार यात्रा की और पटनायक सरकार की तारीफ में जो चंद अल्फाज कहे, उससे विक्षुब्धों को लगा कि अगले चुनाव के बाद शायद तीसरी बार भी उड़ीसा में सत्ता की पतवार इंका आलाकमान पटनायक के हाथ में ही थमाये रखेगा। पटनायक जब दूसरी बार भी मुख्यमंत्री कायम रह गये थे, तो उनके विरुद्ध विक्षुब्धों ने संग्राम छेड़ दिया था। पर विक्षुब्धों के हर हमले के बाद पटनायक और भी दूनी शक्ति से सत्ता की लगाम भींचते रहे। गत वर्ष जब उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी वर्षों बाद कांग्रेस में आयीं और उन्होंने पटनायक पर आते ही धावा बोल दिया, तो विक्षुब्धों को लगा कि नंदिनी का प्रहार शायद ही पटनायक झेल पायेंगे। कुछ दिनों तक सचमुच नंदिनी के हमले से पटनायक घायल होते रहे, पर अचानक उन्होंने दिल्ली दरबार में जाकर 'प्रबंध' कर लिया। फिर राजीव गांधी की उड़ीसा यात्रा किसी-न-किसी कार्यक्रम के बहाने बार-बार होने लगी और पटनायक धीरे-धीरे जमते गये। ये नौ साल पटनायक ने कैसे काटे हैं, यह वाकई दिलचस्प है, क्योंकि पटनायक के पूर्व उड़ीसा में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबको विक्षुब्धों के मारक आक्रमण और राजनीतिक तिकड़मों का शिकार होना पड़ा। पर पटनायक ने अपने कूटनीतिक प्रबंधन से तमाम तिकड़मों को लगातार विफल किया और जोड़-तोड़ के लिए प्रसिद्ध रहे अपने राजनीतिक गुरु हरेकृष्ण महताब से भी वे कई कदम आगे निकल गये। हरेकृष्ण महताब को कई बार उड़ीसा की सत्ता में काबिज होने का मौका मिला था, पर बार-बार महताब सिंहासन से लुढ़कते रहे। गुटबंदी की तीक्ष्ण राजनीति ने सदैव उड़ीसा की सत्ता को अस्थिर बनाये रखा। हरेकृष्ण महताब जब मुख्यमंत्री थे, तो नित्यानंद कानूनगो और गोपबंधु चौधरी उनकी छतरी गिराने पर तुले हुए थे। आखिरकार राजनीति के माहिर खिलाड़ी महताब ने अत्यंत युक्तिपूर्वक नित्यानंद कानूनगो को अपनी तरफ पटाकर मंत्रिमंडल में शामिल करके विक्षुब्ध गतिविधियों को शिथिल करने का दांव लिया। पर इस सबके बावजूद महताब विक्षुब्धों की मुहिम को रोक नहीं सके। आखिरकार पंडित नेहरू ने उन्हें केंद्र में मंत्री पद देकर बुला लिया और महताब के बाद नबकृष्ण चौधरी गद्दी पर बिठाये गये। जानकीबल्लभ पटनायक के पहले अगर कुछ अधिक समय तक किसी मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का सौभाग्य मिला, तो वे नबकृष्ण चौधरी ही थे। पर नबकृष्ण का दीर्घ कार्यकाल भी पटनायक के अब तक के कार्यकाल का लगभग आधा ही था। बहरहाल, नबकृष्ण मुख्यमंत्री तो बन गये थे, पर दिल्ली में बैठे महताब अपने खेमे के विधायकों को उकसा कर उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आते थे। नबकृष्ण की सरकार अपनी सुस्ती के कारण भी तबाह हुई। विकास कार्यों को गति देने में नबकृष्ण कभी सक्रिय नहीं हो सके। नतीजतन, करोड़ों की राशि धरी-की-धरी रह जाती थी। सारे प्रशासन को भूदान आंदोलन में केंद्रित कर और अपनी पत्नी द्वारा चलाये जा रहे अंगुल आश्रम को भारी राशि देकर भी नबकृष्ण विवादास्पद हो गये थे। १९५६ के जनवरी माह में जब कांग्रेस अध्यक्ष यूएन ढेबर उड़ीसा के दौरे पर आये थे, तो विक्षुब्ध विधायकों ने

ढेबर को सहमत कर लिया था कि अगर नबकृष्ण मुख्यमंत्री रह गये, तो १९५७ के चुनाव में कांग्रेस की जीत अनिश्चित है। आखिरकार महताब गुट के अभियान से परेशान होकर नबकृष्ण ने १८ अक्तूबर, १९५६ को इस्तीफा दे दिया। नबकृष्ण के बाद फिर महताब मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हुए। पर इस बार सरकार चलाना महताब के लिए और महंगा पड़ा। मंत्रिमंडल में शामिल न किये जाने से विक्षुब्धों की जमात खतरनाक तेवर अख्तियार किये बैठी थी। इस बार महताब के विरुद्ध विक्षुब्ध गतिविधियों के अगुआ थे बीरेन मित्रा और दीनबंधु साहु। बीरेन तो महताब मंत्रिमंडल में नहीं थे, पर दीनबंधु साहु उनके मंत्रिमंडल में रहकर भी क्षुब्ध चल रहे थे। दरअसल, एक खदान का पट्टा वे मुख्यमंत्री की इच्छानुसार देने को राजी नहीं हुए थे और तब से मुख्यमंत्री महताब से उनकी ठनी हुई थी। यों दीनबंधु ज्यादा दिनों तक महताब के मंत्रिमंडल में रह भी नहीं सके। बहरहाल, घात-प्रतिघात के कड़े दौर में महताब सरकार की हालत खस्ता थी, परिणामस्वरूप १९५९ में एक साझा सरकार का गठन हुआ। इस सरकार के भी मुख्यमंत्री तो महताब ही रहे, पर 'गणतंत्र परिषद्' के आरएन सिंहदेव उपमुख्यमंत्री बनाये गये। चंद महीनों में ही साझा सरकार में तनाव शुरू हो गया और फिर १९६१ में मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गयी। १९६१ के मध्यावधि चुनाव के बाद बीजू पटनायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए। बीजू पटनायक अल्प समय तक ही मुख्यमंत्री रहे, पर एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहचान बनाने की कोशिश जरूर की थी। बीजू पटनायक के पतन के बाद बीरेन मित्रा मुख्यमंत्री बने। बीरेन मित्रा बीजू पटनायक पर इतने आश्रित थे कि बीजू को ही उन दिनों असली मुख्यमंत्री कहा जाता था। बैसाखी के सहारे गद्दी कब तक चलती, सो जल्दी ही मित्रा के सिर से मुकुट उतर गया। फिर आये सदाशिव त्रिपाठी। एक तो सदाशिव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और दूसरे उनके खिलाफ भी विक्षुब्ध बिगुल बजाते रहते थे। लिहाजा, उन्हें भी दो साल के भीतर ही बिस्तर बांधना पड़ा। १९६७ में फिर उड़ीसा में साझा सरकार बनी। 'जन कांग्रेस' और स्वतंत्र पार्टी के योग से बनी इस सरकार के मुख्यमंत्री थे, आरएन सिंहदेव। बाद में दोनों दलों में अनबन तेज हुई और सिंहदेव को इस्तीफा देना पड़ा। सिंहदेव के इस्तीफे के बाद दो दिनों तक उड़ीसा की सत्ता बिलकुल सकते में रही, क्योंकि राज्यपाल ने सिंहदेव को अगले मुख्यमंत्री के चुने जाने तक कामचलाऊ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी थी। लिहाजा, दो दिनों तक उड़ीसा की सत्ता लावारिस स्थिति में रही थी। सिंहदेव के बाद कुछ महीनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, फिर १९७१ का चुनाव आया। इस चुनाव में भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लिहाजा, उत्कल कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी और झारखंड पार्टी ने मिलकर विश्वनाथ दास के नेतृत्व में गैरकांग्रेसी सरकार का गठन किया। पर मिली-जुली इस सरकार को भी जल्दी ही आपसी विवादों और विद्रोह के कारण पतन का मुंह देखना पड़ा। १९७२ के जून माह में जब विश्वनाथ दास की सरकार गिर गयी, तो उत्कल कांग्रेस के सहयोग से नंदिनी सत्पथी ने कांग्रेसी सरकार का गठन किया। पर १९७३ के फरवरी माह में नंदिनी की सरकार तब गिर गयी, जब उनके २५ विधायक 'प्रगति पार्टी' की तरफ खिसक लिये। १९७४ में नंदिनी ने मध्यावधि चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर फिर सरकार बनायी, पर विक्षुब्ध गतिविधियों के कारण उन्हें दुबारा सत्ता से हटना पड़ा। नंदिनी के बाद मुख्यमंत्री बने विनायक आचार्य भी सिर्फ चार माह तक अपनी गद्दी पर रह सके। वे आपातकाल के आखिरी दिन थे। फिर जनता राज आया। नीलमणि राउतराय जनता सरकार के मुख्यमंत्री बने। उस समय केंद्र में मंत्री-पद पर बैठे बीजू पटनायक का भी सहयोग उन्हें प्रदेश की सत्ता चलाने में प्राप्त था। जनता-शासन के पतन के साथ ही नीलमणि भी चले गये। फिर १९८० के चुनाव के बाद सत्ता के महारथी जानकीबल्लभ पटनायक ने उड़ीसा की बागडोर कुछ इस तरह संभाली कि आज नौ साल पार कर वे दसवें साल में दाखिल हैं।

नंदिनी सत्पथी

कुछ दिनों तक सचमुच
नंदिनी के हमले से पटनायक
घायल होते रहे, पर अचानक उन्होंने
दिल्ली दरबार में जाकर 'प्रबंध'
कर लिया।

पटनायक के विरुद्ध चार्जशीट: पटनायक सरकार के नौ साल पूरे होने पर उड़ीसा जनता दल ने पटनायक के विरुद्ध एक चार्जशीट जारी किया। इस चार्जशीट में पटनायक द्वारा अब तक किये गये घपलों व हेरफेर का ब्यौरा है। जून के दूसरे सप्ताह में जनता दल अभियान समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीकांत जेना ने यह यह चार्जशीट जारी की थी। इसमें सबसे प्रमुख आरोप पटनायक द्वारा गलत ढंग से किये गये भूखंड आवंटन का है। मुख्यमंत्री की सांसद पत्नी जयंती पटनायक के नाम नयापल्ली में १९८४ में १४० × १७० फुट के भूखंड आवंटन का मामला काफी जोर से उठाया गया है। आरोप में कहा गया है कि जयंती यह भूमि पाने की हकदार नहीं थीं, क्योंकि उनके पति ने पहले ही शहीदनगर में अपनी जमीन तारिणी चंद्र दास नामक एक व्यक्ति के नाम कर दी थी। पटनायक के दामाद सौम्यरंजन, पटनायक के भाई अमियरंजन पटनायक के नाम भी तीन एकड़ भूखंड आवंटित किये जाने पर आपत्ति की गयी है। मुख्यमंत्री की समधिन कनकमंजरी पटनायक के नाम भी फारेस्ट पार्क क्षेत्र में जमीन का आवंटन किया गया। सौम्यरंजन के एक और भाई दीप्तिरंजन के नाम भी भूमि आवंटित की गयी। चार्जशीट में उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष कान्हूचरण लेंका, पूर्व मंत्री वसंत बिस्वाल, केंद्रीय मंत्री चिंतामणि पाणिग्रही, विधायक ललितमोहन मोहंती तथा न्यायाधीश केसी महापात्र को पक्षपातपूर्ण तरीके से भूखंड दिये जाने का भी प्रसंग है। हां, मजेदार बात यह है कि इस चार्जशीट में पटनायक के दामाद के भाई निरंजन पटनायक जो पटनायक सरकार में मंत्री हैं, पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री के रूप में पटनायक पर लगातार संगीन घपलों के छींटे पड़ते रहे हैं। १९८१ में ६.१ करोड़ रुपए के सरसों के तेल की खरीद के मामले को लेकर पहली बार पटनायक पर जबर्दस्त ढंग से आरोपों की बौछार हुई थी। नौ वर्ष की अपनी सत्ता में पटनायक ने परिवारवाद को जमकर बढ़ावा दिया। अपनी पत्नी जयंती पटनायक को जहां उन्होंने राजनीति में स्थापित किया, वहीं अपने दामाद सौम्यरंजन को एक बड़ा प्रेस-साम्राज्य दिया। सौम्यरंजन इस समय 'संवाद' तथा 'सन टाइम्स' के संपादक हैं। सौम्यरंजन के भाई निरंजन पटनायक सरकार में ताकतवर मंत्री हैं। बहरहाल, उड़ीसा की राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर पटनायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उड़ीसा के अधिकतर मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये घपलों की जांच के लिए पहले ही अनेक आयोग बिठाये जा चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार अब उड़ीसा के लोगों को विचलित नहीं करता। यह तो परंपरा बन चुकी है। २६ अक्तूबर, १९६७ को न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की अध्यक्षता में बीजू पटनायक, बीरेन मित्रा आदि से संबंधित घपलों की जांच के लिए आयोग का गठन हुआ था। इसी तरह हरेकृष्ण महताब पर भी सरजू प्रसाद कमीशन बैठा था। आरएन सिंहदेव पर मित्तर कमीशन तथा नंदिनी सत्पथी पर दास कमीशन बिठाया गया था। बहरहाल, आगे देखना है कि जानकीबल्लभ पटनायक सत्ता के नायक के रूप में कितने वर्षों का रिकार्ड कायम करते हैं।

—विकास कुमार झा, भुवनेश्वर से

अजमेर शरीफ

गरीबनवाज के घर में कलह का राज

लाखों हिंदू-मुसलमान बड़े पवित्र भाव से अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकने पहुंचते हैं, लेकिन दरगाह की व्यवस्था में लगे दीवान, खादिम और नाजिम उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देने के बजाय दरगाह को फसाद का अखाड़ा बनाये हुए हैं। गत २६ मई को तो दरगाह में ही नाजिम व खादिमों के बीच जमकर मारपीट तक हो गयी। आखिर इबादत की यह पाक जगह फसाद की वजह क्यों बन गयी है?

दरगाह में मारपीट : ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह

यह कैसे माना जा सकता है कि अजमेर में आराम फरमानेवाले सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में व्यवस्था के नाम पर नाजिम दरगाह, दीवान दरगाह (सज्जादानशीन) और खादिमों के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उससे ख्वाजा साहब की आत्मा खुश होगी। किंतु इसकी चिंता उन्हें नहीं है जो ख्वाजा के नाम पर पूरी जिंदगी गुजार आये हैं या जिनका भरा-पूरा परिवार आज भी ख्वाजा साहब के ही करम का उम्मीदवार है। अलबत्ता स्थिति तो यह है कि दरगाह की आय में से ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की होड़ में गुटबाजी और छींटाकशी का माहौल गर्म है। उल्लेखनीय है कि दरगाह की प्रबंध व्यवस्था १९५५ से पहले दरगाह दीवान और खादिमों के हाथ में थी। उस दौरान भी दरगाह में दीवान और खादिमों के बीच तनाव था। उस वक्त खादिम यह साबित करने में लगे रहते थे कि तत्कालीन दरगाह दीवान और उनके बुजुर्ग ख्वाजा साहब के वंशज नहीं हैं, तो दरगाह दीवान दस्तावेजों से यह स्थापित करते थे कि दरगाह में खादिमों की हैसियत सेवकों से बढ़कर नहीं है। इसी बीच १९५५ में भारतीय संसद ने दरगाह एक्ट बनाया था। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा पांच साल के लिए ९ सदस्यों की दरगाह कमेटी मनोनीत की जाने लगी। यह कमेटी प्रतिवर्ष अपने में से एक को अध्यक्ष चुनकर दरगाह का नाजिम (प्रबंध व्यवस्था देखनेवाला) नियुक्त करती है। मजे की बात यह है कि तब से आज तक नाजिम की नियुक्ति न खादिमों को पसंद है और न ही दरगाह दीवान को।

नयी व्यवस्था की मार : नयी व्यवस्था के तहत नाजिम की जिम्मेदारी होती है कि वह जायरीनों से अपील करे कि वे नजराने 'नाजिम दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर' को दें अथवा दरगाह शरीफ में रखे हरे रंग के बक्सों में डालें। जाहिर है, जब नाजिम अपनी जिम्मेदारी का कड़ाई से पालन करेगा, तो जिन लोगों की आमदनी में कमी होगी या जिनकी आमदनी खतम हो जायेगी वे चुप कैसे बैठ सकते हैं?

दरगाह कमेटी की ओर से नियुक्त नाजिम इस आय से दरगाह की देखभाल के लिए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन देते हैं तथा जायरीनों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में जो सफाई देखने को मिलती है या जो नया अतिथिगृह बना है वह नाजिम की ही देन है। १९८७ में भी दरगाह की दौलत को हड़पने के झगड़े ने ही तत्कालीन दरगाह नाजिम ब्रिगेडियर एम.ए. खान के सुधारवादी कार्यक्रमों के रास्ते में रोड़े अटकाये थे। वे तो किसी तरह अपना कार्यकाल पूरा कर गये, लेकिन नये नाजिम लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान ने जैसे ही सुधार कार्यक्रम लागू करना शुरू किया, उन्हें खादिमों ने अपमानित करना शुरू कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान की नियुक्ति हुई। उनकी नियुक्ति भी काफी विवादास्पद रही है। सूत्रों का कहना है कि दरगाह कमेटी के पास इस काम के लिए पंद्रह लोगों के नाम आये थे जिसमें से उन्होंने नाजिम पद के लिए तीन लोगों का पैनल बनाया था। बताया जाता है कि पैनल में लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान का नाम तीसरे नंबर पर था, जबकि आजाद तबीयत के अजमेर निवासी ब्रिगेडियर रजा का नाम पहले नंबर पर था। ऐसे में वरीयता क्रम को मद्देनजर रखते हुए नियुक्ति ब्रिगेडियर रजा की होनी चाहिए थी, लेकिन नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान। इस संबंध में जब 'माया' ने जांच-पड़ताल की, तो पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान को नाजिम का पद दिलवाने में सत्ताधारी दल ने खास दिलचस्पी ली थी। इस दिलचस्पी की वजह सिर्फ 'दरगाह दीवान' और

नाजिम के बीच सामंजस्य बिठाना था। दरगाह के खादिम भी इस तथ्य से वाकिफ थे। दीवान दरगाह और नाजिम में संभावित तालमेल की भनक पाते ही उनका यह संदेह मजबूत हो गया कि उन्हें दरगाह दीवान और नाजिम मिलकर उन अधिकारों से वंचित कर देंगे, जिनके लिए उन्होंने दरगाह दीवान को अदालत तक घसीट रखा है। बस फिर क्या था? खादिमों ने नाजिम के खिलाफ मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया। नतीजतन सफाई और सुरक्षा की दृष्टि से किये गये इंतजाम भी खादिमों के लिए आलोचना के विषय बन गये। मसलन नये नाजिम दरगाह ने रात्रि में युवा महिलाओं को इबादत के लिए दरगाह में रुकने पर रोक लगा दी। रमजान के महीने में उन ठेलों को दरगाह के सामने से हटवा दिया जो देर रात तक भीड़ जुटाये रखते थे। यही नहीं, जुमे (शुक्रवार) की नमाज से दो घंटे पहले दरगाह में सफाई के लिए सभी जायरीन को दरगाह से बाहर जाने का भी निर्देश जारी किया गया। हालांकि नाजिम दरगाह के उपर्युक्त निर्देशों में कहीं कोई स्वार्थ दिखायी नहीं पड़ता, किंतु खादिमों ने उनके इन निर्देशों को 'दरगाह में तानाशाही' करार दिया और जमकर नाजिम की आलोचना करने लगे। धीरे-धीरे नाजिम और खादिमों के बीच तनाव ऐसा बढ़ा कि २६ मई '८९ को जब नाजिम दरगाह अपने कर्मचारियों के साथ दरगाह में घूम-घूमकर अपने निर्देश का पालन करवा रहे थे। तभी नाराज खादिमों ने उन पर हमला कर दिया। सूत्रों का कहना है कि नाजिम तथा उनके कर्मचारियों और खादिमों के बीच मजे की मारपीट हुई।

नौबत थाना कचहरी की : नाजिम दरगाह ने इस संदर्भ में नौ खादिमों के खिलाफ अजमेर के गंज थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मजे की बात तो यह है कि खादिमों की अंजुमन (समिति) के सचिव सैयद मुशर्रफ हुसैन ने भी नाजिम दरगाह व उनके कर्मचारियों के खिलाफ अंजुमन के दफ्तर में जबरन घुसने की शिकायत थाने में दर्ज की है।

'माया' ने इस संदर्भ में अंजुमन के संयुक्त सचिव यामिन हाशमी से बात की तो वे बोले, "हमने दरगाह के नाजिम के साथ मारपीट नहीं की। बेवजह लोगों को तंग करते हैं। माइक लगाकर दरगाह में घूमते रहते हैं। इसी से लोग थोड़ा नाराज हो गये थे जिसको उन्होंने मारपीट का नाम दे दिया।" इस पर 'माया' ने सवाल किया, "सुना है आप लोग दरगाह के दानपात्रों में जलती हुई तिल्लियां डाल कर नोट जला देते है?" हाशमी का जवाब था, "यह हमें बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप ही बताइये जो औरतें दरगाह में इबादत करने के लिए रुकती हैं उन्हें जवान होने की वजह से रात को इबादत करने से रोकनेवाले नाजिम दरगाह कौन होते हैं? इसी तरह से हमारे जायरीनों को परेशान किया जाता है।"

یا خواجہ غریب نواز

जायरीन की किसे चिंता है? : दरगाह शरीफ में जायरीन

'माया' ने दरगाह नाजिम ले० कर्नल मोहम्मद उस्मान से इस संदर्भ में बात करनी चाही, तो उनका कहना था, "मुझे कुछ नहीं कहना आप दरगाह दीवान से मिल लीजिये।" नतीजतन दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन खां को टटोला गया तो उनका जवाब था, "मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा आप गलत छापते हैं।" 'माया' ने जानना चाहा कि उसने क्या गलत छापा है, तो उनका कहना था, "आपने दरगाह के संबंध में अपनी पहली रिपोर्ट में उन दस्तावेजों का हवाला नहीं दिया जिससे मैं ख्वाजा साहब का वारिस सिद्ध होता हूं।" उनकी बातचीत का लब्बोलोआब यह था कि वे चाहते थे कि कथा में उन्हीं का पक्ष रखा जाता और खादिमों का पक्ष नजरअंदाज कर दिया जाता।

बहरहाल, दरगाह का जायजा लेने के दौरान 'माया' को यह देखने को मिला कि दरगाह दीवान और नाजिम दरगाह के बीच अब वह दूरियां नहीं हैं जो दो साल पहले नजर आती थीं। घनिष्ठता बढ़ने का कारण सिर्फ ये है कि नाजिम दरगाह तो सत्तारूढ़ दल के तरफदार हैं ही दरगाह दीवान का भी राजनीति से काफी लगाव है। उल्लेखनीय है कि दरगाह दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन खां ने उत्तर प्रदेश में पिछले उपचुनावों के दौरान एक इश्तिहार प्रकाशित किया था जिसमें मुसलमानों से अपील की गयी थी कि वे कांग्रेस-इ और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का साथ दें। यह अपील दरगाह दीवान ने अपने को ख्वाजा साहब का 'नवासा-ए-रसूल' बताते हुए जारी की थी। इस अपील को हजारों की तादाद में छपवाकर सत्तारूढ़ दल ने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी में चिपकवाया था।

सज्जादानशीन पर आरोप : मजे की बात यह है कि दरगाह दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन खां भी व्यवस्था के इस झगड़े का निशाना बन गये हैं। दरगाह के एक खादिम वजीर अली नियाजी जैनुल आबेदीन के बारे में अजीबोगरीब सूचना तो देते ही हैं, साथ में यह भी दावा करते हैं कि जैनुल आबेदीन अपने को 'नवासा-ए-रसूल' और सज्जादानशीन गलत लिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सैय्यद वजीर अली नियाजी ने २२ मार्च, १९८७ को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपनी एक पुस्तक भी जारी की थी। इस पुस्तक में उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की थी कि दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन खां ख्वाजा साहब के वंशज नहीं हैं, फिर भी उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपने को दरगाह का सज्जादानशीन घोषित करवा लिया है। अपनी ३६ पृष्ठों की पुस्तक में नियाजी ने यह भी आरोप लगाया है कि दरगाह दीवान व उनके पिता ने इस संबंध में की गयी जांचों को राजनीतिक असर के इस्तेमाल से अपने पक्ष में किया है।

पुस्तक में यह भी आरोप लगाया गया है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में पर्चा जारी करके उसके एवज में दरगाह दीवान ने रेल सेवा का निःशुल्क यात्रा पास हासिल कर लिया है। पुस्तक के अनुसार दरगाह दीवान का पद बादशाह अकबर ने दरगाह के प्रबंध के लिए बनाया था। इसी प्रबंध के एवज में दरगाह दीवान के नाम कुछ गावों की जागीर सुरक्षित की गयी थी। कालांतर में यह पद बाप से बेटे को मिलने लगा। जब १९५५ में जागीरदारी उन्मूलन नियम लागू हुआ, तो दरगाह दीवान की जागीरदारी समाप्त हुई, जिसका उन्हें मुआवजा दिया गया। नियाजी का दावा है कि

पुस्तक में गंभीर आरोप : सैयद वजीर अली नियाजी

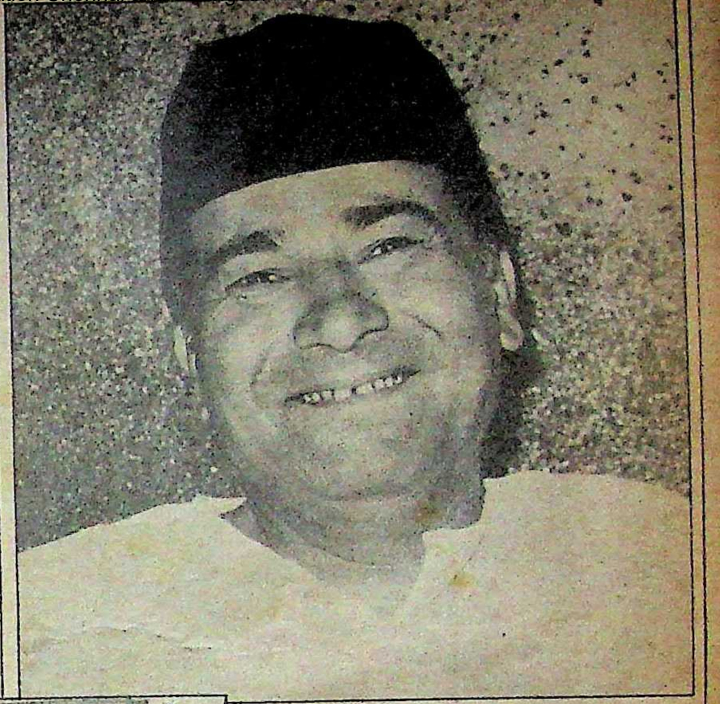

लोग नाजिम से नाराज हैं : यामिन हाशमी

दीवान मुकर्रर करने का जागीरदारी तरीका समाप्त होने के साथ ही दरगाह दीवान का पद भी समाप्त हो गया। प्रमाण के लिए नियाजी दरगाह एक्ट को पढ़ने की सलाह देते हैं, जिसमें उनके अनुसार दीवान के पद का कहीं जिक्र नहीं है।

खादिमों का नजरिया : नियाजी अपनी इसी पुस्तक में यह भी बताते हैं कि दरगाह कमेटी ने दरगाह एक्ट बनने के बाद सज्जादानशीन पद के लिए, तत्कालीन दीवान हकीम इनायत हुसैन की मृत्यु के बाद, आवेदन मांगे थे। हालांकि जागीरदारी के समाप्त होने के बाद दीवान दरगाह का पद समाप्त हो चुका था।

पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि तत्कालीन नाजिम दरगाह ने दरगाह एक्ट की धारा तेरह का उल्लंघन करते हुए दिवंगत दरगाह दीवान के लड़के सैयद सौलत हुसैन से दरगाह दीवान का काम लेना शुरू कर दिया। आरोप है कि जागीर के मुआवजे की सालाना राशि के बारह हजार रुपए भी पूर्व दरगाह दीवान के पुत्र सौलत हुसैन को १९६० से १९७४ तक दिलाये गये। यह सब कुछ हुआ, किंतु सौलत हुसैन को कभी भी दरगाह दीवान नहीं माना गया। १९७५ में आपातकाल के दौरान राजस्थान सरकार के राज्यपाल ने किसी इलमुद्दीन अलीमी को दरगाह शरीफ का सज्जादानशील बना दिया। चूंकि, सैयद सौलत हुसैन ने पहले से इस पद के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई थी इसलिए राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध उन्होंने २३ अक्टूबर, १९७४ को स्टे आर्डर हासिल कर लिया। इसी बीच इलमुद्दीन अलीमी का देहांत हो गया।

सियासत : जैनुल आबेदीन

नियाजी का आरोप है कि सज्जादानशीन के विभिन्न दावेदारों में जैनुल आबेदीन इसी मुकदमे के दौरान उम्मीदवार बने। स्टे आर्डर की शर्तों के अनुसार पंद्रह हजार रुपए का एक जमानतनामा उन्होंने भर दिया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। परिणामस्वरूप जैनुल आबेदीन खां को जागीर कमिश्नर से दरगाह दीवान को मिलने वाला मुआवजा और अन्य लाभ मिलने लगा। नियाजी के मुताबिक जैनुल आबेदीन ने यह सब जालसाजी से हासिल किया।

बदनामी किसकी? : वैसे वजीर अली नियाजी ने अपनी पुस्तक में दीवान दरगाह के संबंध में जो कुछ लिखा है, वह काफी पेचीदा है। पुस्तक को पढ़कर किसी निष्कर्ष पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। 'माया' ने इस संबंध में छानबीन के दौरान जो पाया, वह सिर्फ यह है कि जैनुल आबेदीन के पिता अलीमुद्दीन अलीमी जो अजमेर के जिला रसद अधिकारी थे, ने भारत-पाक विभाजन के बाद सज्जादानशीन पद की दावेदारी के लिए ४१ वर्ष पूर्व मुकदमा दायर किया था। उनके देहांत के बाद फैसला उनके बेटे जैनुल आबेदीन खां के हक में पिछले साल हुआ है।

बहरहाल, ख्वाजा साहब की दरगाह में नाजिम और खादिमों के बीच जो तनातनी चल रही है, उसका परिणाम क्या होगा, यह तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता, किंतु इस तनातनी से एक पवित्र धार्मिक स्थल जिस तरह की राजनीति का अखाड़ा बन रहा है, वह उचित नहीं। फिर सवाल यह नहीं है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के वर्तमान दीवान सैयद जैनुल आबेदीन खां वाकई ख्वाजा साहब के वंशज हैं या नहीं, बल्कि सवाल तो यह है कि ख्वाजा साहब की दरगाह में व्यवस्था के नाम पर जो युद्ध चल रहा है, क्या वह उचित है? जब सरकार ने दरगाह एक्ट बनाकर दरगाह की व्यवस्था के लिए नियम-कायदे बना दिये हैं और काम भी लगभग उन्हीं के अनुसार हो रहा है, तो फिर इस तरह की चीख-पुकार क्यों?

—ओम सैनी

छाया : गोपाल सगा

आजाद की पदयात्राएं

कांग्रेस-इ के गले में घंटी बांधने की कोशिश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने अपनी ताबड़तोड़ पदयात्राओं और जनसभाओं में माफिया के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? वे माफिया के खिलाफ अलख जगाकर क्या मौजूदा कांग्रेस-तंत्र के गले की हड्डी तो नहीं बन रहे ?

आखिल भारतीय कौमी एकता कमिटी
(युवा लीग जिला शाखा)
धनबाद
आपका हार्दिक अभिनन्दन करती है

माफिया से जंग जारी है: धनबाद में पदयात्रा करते हुए भागवत झा आजाद

"आम चुनाव को बस अब चार-पांच महीने ही शेष रह गये हैं, इसलिए बिहार के लोगों, अभी से शपथ लो कि इस बार चुनाव में किसी माफिया को वोट नहीं दोगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का उम्मीदवार क्यों न हो। मुझे यकीन है कि कांग्रेस किसी भी माफिया को टिकट नहीं देगी, पर अगर किसी को दे भी दिया, तो मैं कहता हूं तुम उसे वोट मत देना। वोट का बक्सा खाली भेज देना। याद रखो, अगर इस बार तुम चूक गये और देश की संसद व असेंबली में माफिया को घुसने दिया, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बिहार को कोई नहीं बचा सकेगा। माफिया जब तक राजनीति के कवच में रहेगा, तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए उठाओ हाथ और बोलो कि माफिया को वोट नहीं देंगे।" बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने अपनी पदयात्राओं व जनसभाओं में पिछले दिनों जब यह आह्वान किया, तो उनकी सभा में उमड़ आये जनसमुद्र से हजारों-हजार हाथ उठे और नारे बुलंद हुए—"माफिया को वोट नहीं देंगे। हरगिज नहीं देंगे।" जून माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ आजाद का यह अनोखा चुनाव अभियान राजनीतिक हलकों में दिल्ली से पटना तक सबको चौंका गया कि आखिर आजाद के मंसूबे क्या हैं ? पर आजाद 'माया' से कहते हैं, "मंसूबा बिलकुल साफ है। जिस तरह पुराने किस्से-कहानियों में आप सुनते थे कि अमुक राक्षस का प्राण अमुक जगह के एक पिजड़े में बंद तोते के भीतर सुरक्षित है, ठीक उसी तरह बिहार माफिया अपने प्राण एमपी और एमएलए बनकर बचाता रहा है। इसलिए मैं अभी से लोगों को सचेत कर रहा हूं कि इस बार उन लोगों को अपने प्राण सुरक्षित करने का मौका मत दो। अपने इस आह्वान की शुरुआत मैंने माफिया के दफ्तर धनबाद और माफिया नेता के घर रोहतास से की।"

विवाद की जड़ : वाकई २५ जून को धनबाद और २८ जून को रोहतास में आजाद की पदयात्रा और जनसभा सुर्खियों में रही। पिछले कुछ महीनों में धनबाद कांग्रेसी दंगल का केंद्र बन गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र की धनबाद-यात्रा से विवाद का सूत्रपात हुआ। दरअसल, धनबाद में जगन्नाथ मिश्र जब अति विवादास्पद नौरंगदेव सिह के यहां अल्पाहार हेतु गये, तो इसको लेकर काफी टीका-टिप्पणी हुई और जगन्नाथ मिश्र के आलोचकों ने कहना शुरू किया कि माफिया से प्रदेश इंका अध्यक्ष के रिश्ते साबित हो गये। धनबाद की अपनी उसी यात्रा के दौरान जब जगन्नाथ ने यह भी बयान दे दिया कि धनबाद के पूर्व उपायुक्त मदनमोहन झा सिर्फ आत्मप्रचार के लिए माफिया से लड़ने का नाटक करते रहे, तो इस बात पर भी भारी प्रतिक्रिया हुई कि ऐसा कहकर जगन्नाथ मिश्र एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को विवादास्पद बना रहे हैं जिसने लगातार धनबाद में माफिया से लड़ाई मोल ली। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आजाद ने मदनमोहन को धनबाद के उपायुक्त पद पर तैनात किया था। पर सत्येंद्र नारायण सिह ने जब मदनमोहन का तबादला धनबाद से कर दिया, तो यह चर्चा का विषय बन गया कि धनबाद में माफिया की जड़ों को सींचने के लिए ही माफिया से मुठभेड़ करनेवाले उपायुक्त को बदल दिया गया। मदनमोहन के हटने के बाद जिस दिन जगन्नाथ मिश्र धनबाद गये थे और नौरंगदेव सिह के घर जाने की चूक कर दी थी, उसी दिन उत्साह में नौरंगदेव के भाई रामचंद्र सिह ने पिछले कुछ दिनों से धनबाद प्रशासन द्वारा जब्त अपने पेट्रोल पंप 'कामधेनु' पर जाकर पुलिसवालों को वहां से खदेड़ दुबारा अपना कब्जा जमा लिया था। इस वाकये को लेकर जब भारी बावेला मचा, तो मुख्यमंत्री सत्येंद्रनारायण सिह ने फोन कर धनबाद के आरक्षी अधीक्षक को हिदायत दी कि फौरन रामचंद्र सिह को पेट्रोल पंप से खदेड़ा जाये। बहरहाल, काफी शोर-शराबे के पश्चात विवादास्पद पेट्रोल पंप से रामचंद्र सिह को प्रशासन ने हटाया। इन प्रसंगों के पश्चात पूर्व बिहार इंका अध्यक्ष तारिक अनवर धनबाद में सभा करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर वे आलाकमान से जगन्नाथ मिश्र की शिकायत करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी धनबाद यात्रा के दौरान माफिया की हौसला-अफजाई की।

आजाद की यात्रा: २५ जून को भागवत झा आजाद के धनबाद-आगमन पर अद्‌भुत दृश्य देखने को मिला। आजाद की पदयात्रा और जनसभा में अपार भीड़ उमड़ पड़ी। स्वयं आजाद को भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। दरअसल, धनबाद के मजदूरों व आम लोगों में यह कौतूहल था कि माफिया से लड़कर अपनी गद्दी गंवा देनेवाला आदमी क्या कहने आया है? यों आजाद की धनबाद यात्रा विगत १ मई को ही होनी थी और निरसा के इंका विधायक कृपाशंकर चटर्जी ने आजाद के कार्यक्रम की तैयारी का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। पर जब चटर्जी महाशय को इस बात का इलहाम हुआ कि आजाद-मार्च में कदमताल करने से वे एक साथ मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की निगाह में चुभ जायेंगे, तो उन्होंने आजाद के कार्यक्रम से पहले ही कन्नी काट ली। पर इसके बावजूद आजाद ने धनबाद-यात्रा को रद्द नहीं किया। उन्होंने धनबाद के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा, "मुझे न तो मंच चाहिए, न कोई आयोजक। सिर्फ धनबाद के लोगों को सूचना दिलवा दो कि मैं १ मई को आऊंगा।" पर अचानक आजाद को १ मई का अपना पूर्व घोषित धनबाद-कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि ऐन १ मई को मुख्यमंत्री धनबाद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से टकराव टालने के लिए आजाद ने कार्यक्रम आगे की तारीख के लिए सरका दिया। पर मुख्यमंत्री भी आखिरी वक्त में धनबाद नहीं गये और उस दिन सूर्यदेव सिंह की रिहाई की खुशी में धनबाद में विजयोत्सव मनाया गया।

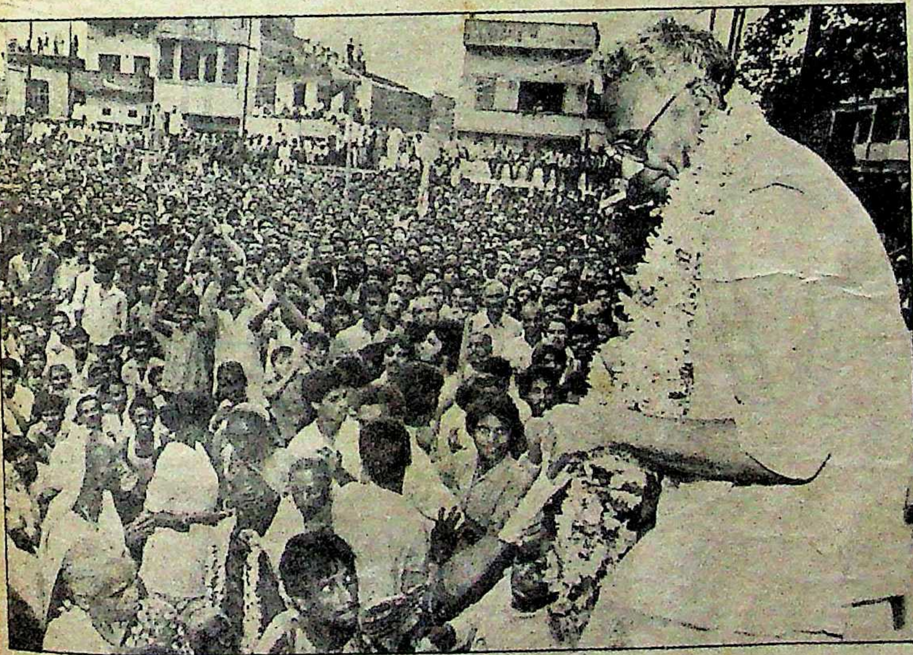

जनता का ही सहारा: धनबाद में आयोजित आम सभा में आजाद

१७ जून को आजाद को दिल्ली दरबार में बुलाया गया, तो राजनीतिक हलकों में खबर उबलने लगी कि आजाद को केंद्रीय काबीना में शामिल करने के लिए तलब किया गया है। पर जब मंत्रिमंडल-विस्तार का मामला टल गया, तो २३ जून को आजाद पटना आ गये और २५ जून को धनबाद में अपने कार्यक्रम के लिए कूच कर गये। आजाद ने धनबाद में श्रमिक चौक से लेकर झरिया के चिल्ड्रेन पार्क तक कई किलोमीटर की पदयात्रा की। आजाद के इस कारवां में कोयला खदानों में काम करनेवाले मजदूर-मजदूरिनों की संख्या हजारों में थी। पदयात्रा के दौरान तब हलचल मच गयी, जब आजाद, रामचंद्र सिंह के कामधेनु पेट्रोल पंप पर स्वयं गये और उस जनता भवन के परिसर में भी जिसे आजाद ने अपनी हुकूमत के दौरान धनबाद के 'राजा' सूर्यदेव सिंह के चंगुल से मुक्त कराया था। लगभग १२ किलोमीटर तक की इस पदयात्रा के रास्ते में अनगिनत जगह माफिया विरोधी बैनर लगे थे। अपनी आम सभा में आजाद ने तकरीबन एक घंटे का विस्फोटक भाषण दिया और वही बात दुहरायी—"शपथ लो कि आनेवाले चुनाव में माफिया को वोट नहीं देंगे।" आजाद के इस इसरार पर हजारों हाथ समर्थन में लहरा उठे। आजाद ने कहा, "चोर चोरी करता है और भाग जाता है, डाकू डाके डालने के बाद एक पल नहीं रुकता और बादशाह जब राज को लूटता है, तो प्रजा का पांव पकड़ता है कि मुझे माफ कर दो। पर माफिया लूटता भी है और हेकड़ी के साथ डटा भी रहता है।" आजाद ने रोहतास की अपनी सभा में भी कहा, "क्या तुम लोग चाहते हो कि फिर हर साल तुम्हें खाद की जगह बालू मिले? तुम्हारी फसलें जलकर राख हो जायें? इसी चुनाव में तुम्हें तय कर लेना होगा यह सब!" रोहतास जिले के विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र से बिहार के सहकारी महंत तपेश्वर सिंह इंका के सांसद हैं। आजाद ने विक्रमगंज में भी जनसभा की।

अभियान का अर्थ: आजाद की इन दो जनसभाओं व पदयात्रा को जैसा जनज्वार मिला, उसने सबसे ज्यादा कांग्रेसी हलके में बेचैनी पैदा कर दी है। पर आजाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के मुताबिक उनका यह अभियान जारी है। आजाद की ललकार आखिर क्या गुल खिलायेगी? सचमुच हजारों हाथों से कांग्रेसी झंडे और पताके का परचम लहरा कर आजाद जिस बात की ताकीद कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगर तपेश्वर सिंह जैसे लोगों को फिर से टिकट देने की कांग्रेस ने गलती की, तो आजाद का आह्वान कांग्रेस के लिए चुनाव में भीषण संकट उत्पन्न कर देगा। आजाद बिहार की जनता के बीच जिस तरह के प्रतिनिधि चुनने की कसौटी बता रहे हैं, उस आधार पर कांग्रेस के आधे से अधिक वर्तमान सांसदों व विधायकों की खाट खड़ी हो जायेगी। डा० जगन्नाथ मिश्र जब सत्ता से हटे थे, तो जन-जागरण की शुरुआत कर उन्होंने नारा दिया था कि केंद्र बिहार को उसका जायज हक नहीं देता है, इसलिए बिहार आगे नहीं बढ़ पाया है। पर जगन्नाथ ने यह नारा अकसर उस मंच से दिया जहां तपेश्वर सिंह जैसे महंत पालथी मारे बैठे रहते थे। पर आजाद जड़ पर चोट कर रहे हैं। सासाराम की सभा में जैसा कि उन्होंने कहा, "सिर्फ तेरह माह तक सत्ता के भीतर रहकर मैंने देखा कि यह ठीक है कि यह प्रांत गरीब है और इसके साधन अत्यंत नगण्य हैं, पर कम साधन का भी अगर ईमानदारी से इस्तेमाल हो, तो इस सूबे की किस्मत चमक सकती है। मैंने तो इंजीनियरों को बुलाकर इतना ही कहा था कि अगर हमारी सड़कें, हमारे स्कूलों के भवन, हमारे पुल और बांध पहले की तरह निर्धारित समय से पूर्व टूटे, तो तुम लोग भी तोड़ दिये जाओगे।" जगन्नाथ व आजाद में यही मूलभूत अंतर है कि जगन्नाथ सदैव साधन-वृद्धि की बात करते रहे हैं और आजाद कहते हैं कि हमारे पास जो भी साधन हैं, उनके सही इस्तेमाल से भी हम तरक्की कर सकते हैं।

राजनीतिक पंडित गणित जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी १९९० की राजनीति कर रहे हैं—सत्येंद्र नारायण सिंह भी, जगन्नाथ मिश्र भी और भागवत झा आजाद भी, पर तीनों अपने-अपने तरीके से। सत्येंद्रनारायण सिंह जहां सबको मिलाकर चलनेवाले नेता की छवि तैयार करने में व्यस्त हैं, वहीं जगन्नाथ मिश्र सत्ता के मौजूदा चरित्र की मांग पूरी करनेवाले नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित किये बैठे हैं और आजाद एक तीसरे कठिन विकल्प की जमीन तैयार करने में जुटे हैं, जिसके तहत सत्ता का चरित्र पूरी ईमानदारी से जनहित के अनुरूप हो। इसलिए वे अपनी पदयात्राओं में यह कहकर अलख जगा रहे हैं, "इसी चुनाव में तय करना होगा कि तुम्हें खाद चाहिए या खाद की जगह बालू। मजबूत सड़क, बांध और पुल चाहिए या हर चार महीने पर बनकर टूटनेवाली सड़कों, पुलों और बांधों के अवशेष?"

—विकास कुमार झा

छोटे साहब के सौ दिन

सत्येंद्र नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बने सौ दिन हो गये।
इतने कम समय में ही उनकी सफलताओं के बड़े-बड़े दावे उनके समर्थक करने लगे हैं।
पर कितने सही हैं ये दावे ?

मोह से मुक्त : मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह

२३ जून की शाम मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह औरंगाबाद से वापस पटना लौटे ही थे कि तभी बोरिंग रोड स्थित उनके निवास पर केंद्रीय मंत्री तथा बिहार संबंधी समन्वय समिति के प्रभारी भजनलाल का फोन आया। भजनलाल ने सत्येंद्र नारायण सिंह से कहा कि अगले दिन यानी २४ जून को वे दिल्ली आ जायें, ताकि बिहार में मंत्रिमंडल-विस्तार के प्रसंग में आलाकमान से बातचीत कर ली जाये। लेकिन सत्येंद्र नारायण सिंह ने दोटूक कह दिया कि वे किसी सूरत में नहीं पहुंच सकते, तो भजनलाल तो अचकचा कर रह गये। भजनलाल ने जब फिर इसरार किया, तो सत्येंद्र ने कहा कि राज्य सरकार का विमान अभी आर्डर में नहीं है और वैसे भी मेरा दिल्ली आना अभी संभव नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल-विस्तार की बातचीत आप स्वयं कर लें और मुझे सूचित कर दें। सत्येंद्र नारायण सिंह की ये बातें फोन पर सुनकर भजनलाल समझ गये कि उनकी नाराजगी शायद अभी तक कायम है। लिहाजा, भजनलाल ने आरके धवन को फौरन फोन कर कहा कि एक बार वे भी पटना फोन कर सत्येंद्र नारायण सिंह से दिल्ली आने को कहें। धवन ने जब पटना फोन किया, तो उन्हें भी सत्येंद्र बाबू ने वही उत्तर दिया। १९ जून को सत्येंद्र नारायण सिंह व जगन्नाथ मिश्र को बिहार मंत्रिमंडल तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन संबंधी मामले पर अंतिम रूप मे निर्णय लेने के लिए भजनलाल ने दिल्ली बुलाया था। पर जब उस यात्रा में भी मंत्रिमंडल-विस्तार का मामला फंस गया, तो जानकारों के मुताबिक सत्येंद्र नारायण सिंह २१ जून को नाराज होकर पटना लौट आये। सत्येंद्र बाबू की नाराजगी की खबर जब दिल्ली दरबार को मिली, तो भजनलाल से कहा गया कि वे सत्येंद्र बाबू को इत्तिला दें कि २४ जून को आकर वे सारी बातें तय कर लें। पर सत्येंद्र बाबू ने ठान लिया कि नहीं जाना है, सो नहीं ही गये। उनसे नाराजगी के बाबत पूछे जाने पर उनका कहना था, ''नाराजगी जैसी कोई बात थी ही नहीं। बस कुछ 'कम्युनिकेशन गैप' हो गया था।'' पर दिल्ली के खास सूत्र 'माया' से बताते हैं कि आरके धवन सत्येंद्र-मंत्रिमंडल का विस्तार होने में सदैव ऐन वक्त पर अड़ंगा लगा देते हैं। राजनीतिक खिलाड़ियों का कहना है कि धवन ने सत्येंद्र नारायण सिंह को अपने मंत्रिमंडल की सूची में कुछ नामों को शामिल करने का निर्देश दिया, पर सत्येंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। लिहाजा, धवन खुंदक खा गये। सत्येंद्र बाबू के करीबी लोगों के मुताबिक धवन को यह बात सदैव से अखरती रही है कि अपनी किसी भी दिल्ली यात्रा के दौरान सत्येंद्र नारायण सिंह उनसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। दरअसल, सत्ता के उपकेंद्रों पर जाकर हाजिरी बजाने की जरूरत सत्येंद्र इसलिए नहीं समझते, क्योंकि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव पर पता नहीं कितने दिन और उन्हें सत्ता में रहने दिया जाये, इसलिए वे दरबार के मुलाजिमों का दरबार भला क्यों करने जायें ?

मई महीने के अंतिम सप्ताह में जब सत्येंद्र नारायण सिंह दिल्ली से वापस लौटे थे, तो उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र कर दिया जायेगा। पर उसी दौरान बिहार के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की मां का निधन हो गया और ३१ मई तक के लिए पहाड़िया राजस्थान चले गये थे। लिहाजा, कहा यह गया कि राज्यपाल की अनुपस्थिति के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया। पर बाद के दिनों में भी जब गाड़ी आगे नहीं

साक्षात्कार/सत्येंद्र नारायण सिंह

'मुझे किसी चीज से मोह नहीं है'

मंत्रिमंडल की बैठक बस थोड़ी ही देर बाद होनी थी। इसीलिए पटना सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री के कक्ष में उनके कई मंत्री पधार चुके थे। तभी मुख्यमंत्री के फोन की घंटी बजी। फोन पर एक दिग्गज नेता थे। वे किसी अफसर का तबादला उसी दिन काबीना की बैठक में कर देने की मिन्नत कई मिनटों तक मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह से करते रहे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने परेशान होकर कहा—"भई, यह बिहार है। थोड़ा भी इधर-उधर होगा, तो हंगामा मच जायेगा।" सचमुच सत्ता का संचालन और वह भी बिहार में, सीधी खीर नहीं है। अपने दल के लोगों का दिल, भरसक रखते हुए सत्येंद्र नारायण सिंह ने सत्ता के अपने ये सौ दिन कैसे पूरे किये? 'माया' से उनकी बातचीत के अंश :

माया : २४ जून को दिल्ली बुलाये जाने के बावजूद आप नहीं गये। राजनीतिक हलकों में इस बात की जोरों से चर्चा है कि १९ जून की अपनी दिल्ली यात्रा में आप धवन द्वारा अपने मंत्रिमंडल विस्तार की

बढ़ी, तो सत्येंद्र की झुंझलाहट स्वाभाविक थी। मात्र एक दर्जन मंत्रियों के दम पर सरकार चलाना सत्येंद्र के लिए दूभर हो रहा है, क्योंकि अभी सबके-सब काबीना मंत्री ही हैं, राज्यमंत्री एक भी नहीं। दरअसल, सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में अपनी लाबी मजबूत करने के लिए सत्येंद्र नारायण सिंह कभी उत्सुक हुए ही नहीं। न वे धवन के पास गोट जमाने गये, न सतीश शर्मा और न ही शीला दीक्षित के पास। सत्येंद्र नारायण सिंह को यही कमी आज परेशानी में डाले हुए है। दूसरे, उनके खिलाफ इंका के खजांची सीताराम केसरी सरीखे लोग भी दरबार में पलीता बिछाने में जुटे हुए हैं। केसरी क्षुब्ध हैं कि सत्येंद्र, श्याम सुंदर धीरज सहित उनके चंद शिष्यों को कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों केसरी पटना आये थे। उन्होंने अनगिनत बार मुख्यमंत्री निवास पर फोन किया कि वे मुख्यमंत्री से तत्काल मिलना चाहते हैं, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दरअसल, सत्येंद्र नारायण सिंह समझते हैं कि केसरी को तरजीह देने का मतलब है बिला वजह पचड़े में पड़ना। सत्येंद्र-समर्थकों का कहना है कि केसरी, ललितेश्वर शाही या ऐसे किसी नेता को खुश करके रखने के चक्कर में पड़ना सत्येंद्र को गवारा नहीं, क्योंकि न तो इन लोगों के दम पर सत्येंद्र को पद मिला है और न छिनेगा। राजनीति में आप परिस्थिति के मुताबिक फिट बैठते हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र जानते हैं कि परिस्थितियों ने उन्हें पद दिलाया है और परिस्थितियां ही उनसे यह पद ले भी सकती हैं। इसी कारण सत्येंद्र सिंहासन पर बैठकर भी तटस्थ हैं। इसी सोच के तहत सत्येंद्र की यह ठंडी तटस्थता दिल्ली दरबार के सूबेदारों को तिलमिला रही है।

उपलब्धियों का गाना : सत्येंद्र नारायण सिंह अपनी सत्ता के सौ दिन पार कर चुके हैं। महज सौ दिनों में किसी सरकार की सफलता या विफलता पर बहस बेमानी है, पर सत्येंद्र के समर्थक अपनी उपलब्धियों का दावा करते नहीं थकते। उनके मुताबिक सत्येंद्र नारायण सिंह ने गद्दी पर बैठते ही महीनों से चली आ रही शिक्षक हड़ताल को समाप्त करवा दिया, मध्य बिहार में होनेवाली हिंसा रुक गयी, सहकारिता माफिया पर मामले चलाये गये और धनबाद माफिया के विभिन्न अड्डों पर छापामारी की गयी। जबकि तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि हजारीबाग में लगभग एक महीने तक दंगा जारी रहा, बेगूसराय में खूनी खेल हुआ, भागलपुर की कचहरी में गोली चली और ऐसे अनगिनत वाकये हुए। सत्ता के इन सौ दिनों में पुलिस द्वारा तकरीबन ३०-३१ जगहों पर फायरिंग की गयी। सत्ता के सौ दिनों में विकास कार्यों पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी नौकरशाही में उलटफेर करना समझा गया। सौ दिनों में सत्येंद्र नारायण सिंह ने छह दर्जन से अधिक नौकरशाहों को इधर-उधर खिसकाया, मानो सरकार का यही एकमात्र काम हो। पर सत्येंद्र के करीबी कहते हैं कि चुनाव वर्ष है और हरेक सांसद तथा विधायक अपने क्षेत्रों में अपनी तबीयत

सूची में हस्तक्षेप करने के कारण नाराज होकर चले आये थे?

सत्येंद्र नारायण सिंह : *ये चर्चाएं बिलकुल बेबुनियाद हैं। आरके धवन ने कभी भी किसी स्तर पर मेरे मंत्रिमंडल-विस्तार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मंत्रिमंडल का विस्तार समय पर हो जायेगा।*

माया : *आपकी सरकार के सौ दिन पूरे हो गये। इस अवधि में अपनी सरकार की क्या उपलब्धि मानते हैं आप?*

सिंह : *मेरी उपलब्धियों के बारे में मुझसे बेहतर बिहार की जनता से पूछिए। वही असली निर्णायक है। हां, इतना मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि प्रदेश तनाव के माहौल से मुक्त होकर इतने दिनों के अंतराल में एक सहज स्थिति में जरूर आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इसके पहले कभी भी प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए इतनी बड़ी घोषणा नहीं की थी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार एक बेहद खुशहाल प्रांत हो और निरंतर तरक्की करे। प्रदेश में बहुत सारी विकास परियोजनाओं को कारगर करने की दिशा में मैं जुटा हूं। पेयजल-संकट को प्रदेश से दूर करने में हमें कामयाबी मिली है। सिंचाई के मामले में भी हमने कदम बढ़ाये हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी पूरा बल दिया है। प्रदेश में एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण कायम करने की जरूरत है और वह किया जा रहा है। मध्य बिहार का इलाका जो सदैव से अशांत रहता आया है, वहां अब अमन है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या करने की सोचता हूं, उसके पीछे वह विश्वास और सद्भाव ही मेरा संबल है जो बिहार के लोगों ने शुरू से अब तक मुझे दिया है।*

माया : *डा० जगन्नाथ मिश्र से आपके तनाव की चर्चा रह-रहकर गर्म होती रहती है। आखिर इसमें सचाई क्या है?*

सिंह : *मैं अपनी तरफ से किसी से मतभेद नहीं रखता। दरअसल, तनाव या टकराव वहां होता है, जहां कुछ स्वार्थ या मोह होता है। मुझे किसी भी चीज से मोह नहीं है, फिर टकराव किस बात का? कृष्णबल्लभ सहाय जब मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में नंबर दो का दर्जा दिया था। मैंने उनसे कहा भी कि यह दर्जा बेहतर हो किसी और को दे दीजिए। पर वे नहीं माने। जब कभी कृष्णबल्लभ बाबू मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आ पाते थे, तो स्वाभाविक रूप से नंबर दो होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठक में मुझे अध्यक्षता करनी होती थी। पर ऐसे मौकों पर मैं जानबूझ कर अनुपस्थित हो जाता था, ताकि महेश बाबू बैठक की अध्यक्षता करें। १९६६ में श्रीमती गांधी चाहती थीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, पर इस बात पर कम लोग विश्वास करेंगे कि मैंने उनसे कहा था कि यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दीजिये। मैं कभी महत्वाकांक्षी रहा ही नहीं, इसलिए कभी किसी से न तो टकराव हुआ, न मतभेद। मैं इलाहाबाद में स्व० लालबहादुर शास्त्री के घर पर रहकर पढ़ा। वे मेरे अभिभावक जैसे थे। पंडित विनोदानंद झा के मंत्रिमंडल में जब मैं पहली बार मंत्री बना, तो कागज की एक चिट पर शास्त्रीजी ने मुझे एक पंक्ति लिख कर थमा दिया था कि पांच साल से पहले अपने पद से कोई और परिवर्तन की बात मत सोचना। दरअसल, उन्हें लगा कि मंत्री बनने के बाद जल्दी ही कहीं मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में न लग जाऊं। मेरी राजनीतिक दीक्षा जिस परिवेश में हुई, वहां मैंने यही सीखा कि अति महत्वाकांक्षा कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग जगन्नाथ मिश्र से मेरे तनाव की बातें करते हैं, वे मुझे ठीक से जानते ही नहीं। मेरा तनाव किसी से हो ही नहीं सकता।*

माया : *माफिया को ठिकाने लगाने के लिए क्या आपकी सरकार कुछ कर रही है?*

सिंह : *बेशक! सहकारिता के क्षेत्र में जो लोग आरोपों के घेरे में थे, उन पर मामला चला दिया गया है। धनबाद में गलत तत्वों पर पिछले दिनों जबर्दस्त छापामारी हुई। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के हित पर जो वार करेगा, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कार्रवाई जोर-शोर से हो रही है। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक दिन हंगामा किया जाये।*

माया : *आपकी सरकार में अधिकारियों के तबादले थोक के भाव हो रहे हैं और आरोप यह भी है कि एक जाति विशेष के अधिकारी लाभ के पदों पर तैनात किये जा रहे हैं?*

सिंह : *आलोचना और आरोप लगानेवालों का यही चरित्र होता है कि बस वे आंख मूंद कर आलोचना करते रहें। तबादले नियमानुसार हो रहे हैं। हां, अगर ऐसा होता, तो मैं मुख्य सचिव पद पर एयू शर्मा और पुलिस महानिदेशक पद पर एके चौधरी को क्यों लाता?*

माया : *आगामी चुनाव में बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी?*

सिंह : *बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। लोग समझ चुके हैं कि उनके हितों की रक्षा कांग्रेस और राजीव गांधी के जरिये ही हो सकती है। कांग्रेस को प्रबल बहुमत मिलेगा यहां।*

—विकु झा

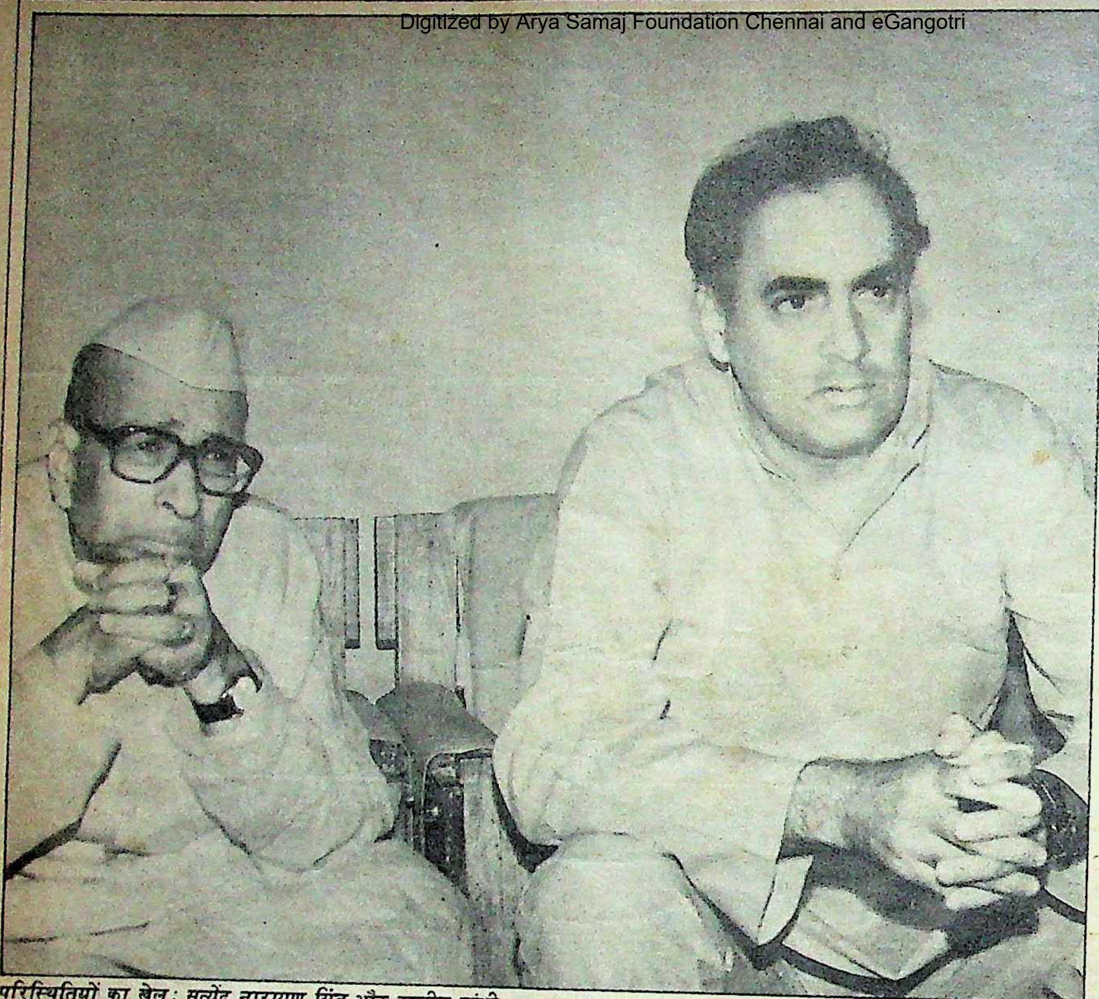

परिस्थितियों का खेल : सत्येंद्र नारायण सिंह और राजीव गांधी

सत्येंद्र-सरकार के इन सौ दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धि यही कही जा सकती है कि इतने दिनों तक सत्येंद्र ने कांग्रेस के अंदरूनी पारंपरिक संग्राम को टाले रखा।

का विश्वासपात्र अधिकारी ले जाना चाहता है, इसलिए तबादले हो रहे हैं। यों ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए शुरू में सत्येंद्र ने पुलिस महानिदेशक पद पर एक चौधरी को बिठा दिया, पर इसके बावजूद सत्येंद्र इस आरोप के शिकार हो रहे हैं कि वे ब्राह्मण अफसरों को 'शंट' कर रहे हैं। २० मई को सत्येंद्र ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल के दौरान दूसरी बार व्यापक प्रशासनिक उलटफेर कर १६ आईपीएस अफसरों को ठिकाने लगाया। भागवत झा आजाद के मुख्यमंत्रित्वकाल में विशेष शाखा के आरक्षी महानिरीक्षक रहे सुधीर कुमार झा को खेल प्राधिकरण में निदेशक पद पर भेज दिया गया, इसी तरह नारायण मिश्र जैसे वरिष्ठ अधिकारी को बिजली बोर्ड में सूखने के लिए भेज दिया गया। पूर्णिया के जिलाधिकारी पद पर जहानाबाद के उपविकास आयुक्त विजय प्रकाश को पहले भेजने और फिर वापस किये जाने का मामला भी काफी दिलचस्प रहा। विजय प्रकाश को जब पूर्णिया में पदस्थापित किया गया, तो कुछ लोगों ने इस पर काफी बावेला मचाया। लिहाजा तत्काल विजय प्रकाश को साहेबगज भेज दिया गया। मुख्यमंत्री के संबंधी एनके सिंह, जिन्हें अतिरिक्त वित्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गयी, प्रशासनिक फेरबदल के सूत्रधार बताये जाते हैं।

सत्येंद्र के इन सौ दिनों में दावा यह भी किया गया कि राज्य सरकार की पहल से रेल मंत्रालय अब बिहार की रेल परियोजनाओं को कारगर करेगा जो अब तक फंसी थीं। सरकार ने दावा किया कि दरभंगा-समस्तीपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी, वह पूरी कर दी जायेगी और छितौनी रेल पुल का निर्माण कराया जायेगा। पर ये बातें महज दावे तक ही सीमित हैं। मुख्यमंत्री को रेलमंत्री माधवराव सिंधिया से खुद बात करनी थी, पर समयाभाव के कारण न तो मुख्यमंत्री माधवराव से बात करने गये और न ही रेल परियोजनाओं के संदर्भ में कुछ ठोस नतीजा निकल सका।

हां, सत्येंद्र-सरकार के इन सौ दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धि यही कही जा सकती है कि इतने दिनों तक सत्येंद्र ने कांग्रेस के अंदरूनी पारंपरिक संग्राम को टाले रखा। बीससूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर तारिक अनवर को बरकरार रखने की बात से जब जगन्नाथ मिश्र ज्यादा दुखी होने लगे, तो मुख्यमंत्री ने तारिक को हटाकर उन्हें वह कुरसी सौंप दी तथा लगे हाथ तारिक को भी अल्पसंख्यक संबंधी एक समिति की जिम्मेदारी सौंप दी। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही से सत्येंद्र ने अपने पुराने कटु संबंध सुधारे, वहीं शाही के कट्टर विरोधी मुजफ्फरपुर के इंका विधायक रघुनाथ पांडे को भी काफी तरजीह दी। फिर सहकारिता के मामले में रघुनाथ पांडेय पर सरकार ने १४ जून को मुकदमा भी कर दिया। १० जून को सत्येंद्र ने सहकारी महंत तपेश्वर सिंह के साथ रोहतास में सभा की और ठीक चार दिन बाद तपेश्वर पर सरकार ने केस भी दर्ज कर दिया।

इन सौ दिनों में भूमि सुधार की दिशा में भी सरकार की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं हुई। सिंचाई का मामला वैसा ही ठप रहा और प्रदेश के विश्वविद्यालय भी खस्ताहाली के दौर से जूझ रहे हैं। पानी और बिजली का संकट राजधानी तक में बुरी तरह व्याप्त है। राजधानी में अपराध के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है।

—विकास कुमार झा

छाया दीपक कुमार

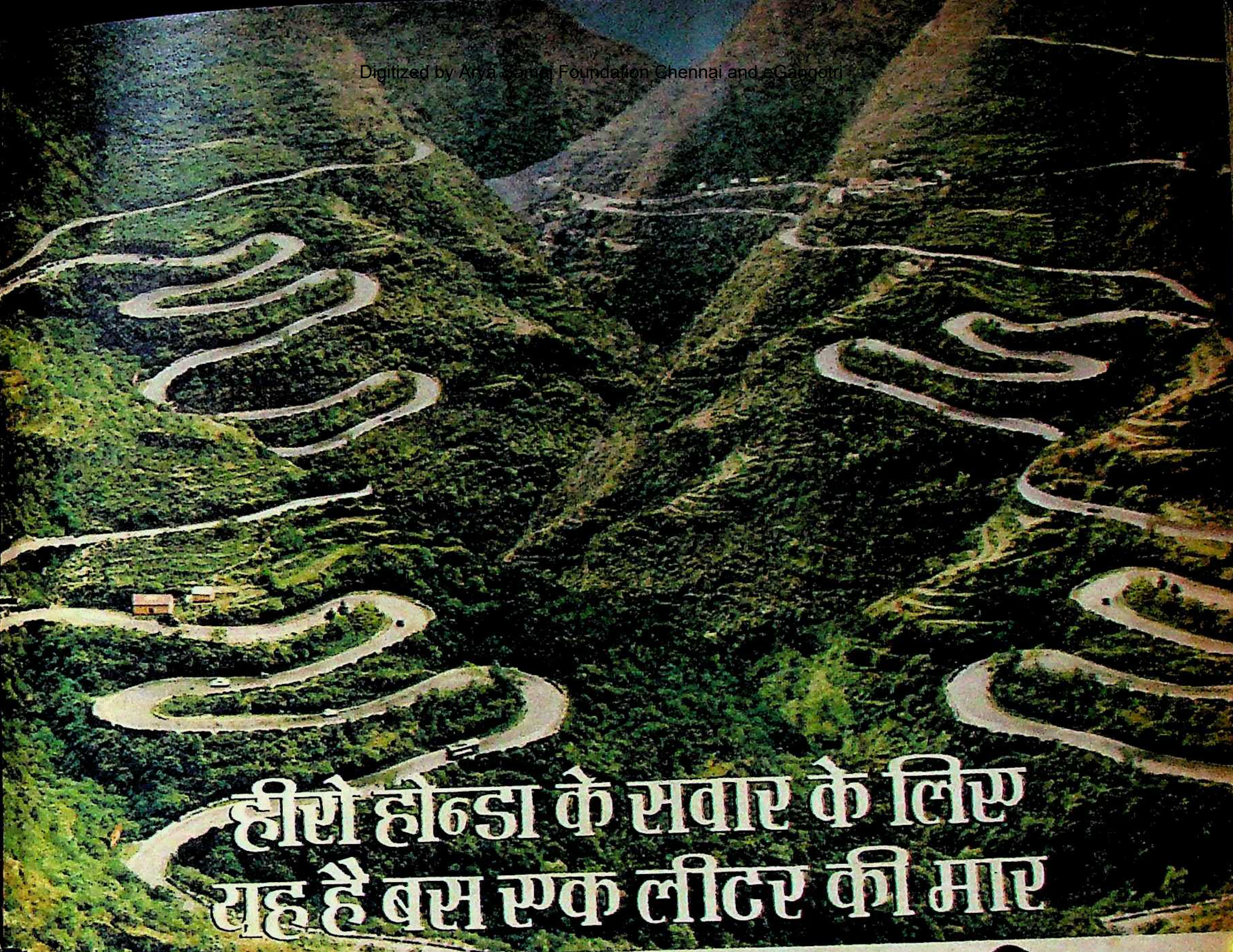

हम यह बात ज़रा भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहे। अगर आप हीरो होन्डा सी डी 100 पर सवार हैं तो एक लीटर पेट्रोल आपको बहुत दूर—80 किलोमीटर दूर तक—ले जाएगा।

एक लीटर में आपको *इतनी* दूर भला और कौन सी मोटरसाइकिल ले जाएगी?

टैंक भरिए. और चलते चलिए.

होन्डा की तकनीकी श्रेष्ठता हीरो होन्डा सी डी 100 के असाधारण 4-स्ट्रोक इंजन की हर विशेषता में देखी जा सकती है। ईंधन पूरी मात्रा में जलने के कारण देखभाल में आसानी, 80 किलोमीटर प्रति लीटर* चलने की कुशलता, और साथ में प्रदूषणहीन एग्ज़ास्ट सुनिश्चित हैं—मीलों मील बिना-परेशानी अच्छी सेवा के लिए।

हां, हीरो होन्डा को लाखों ने अपनाया है। उन्हीं ने इसे भारत की सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिल बनाया है।

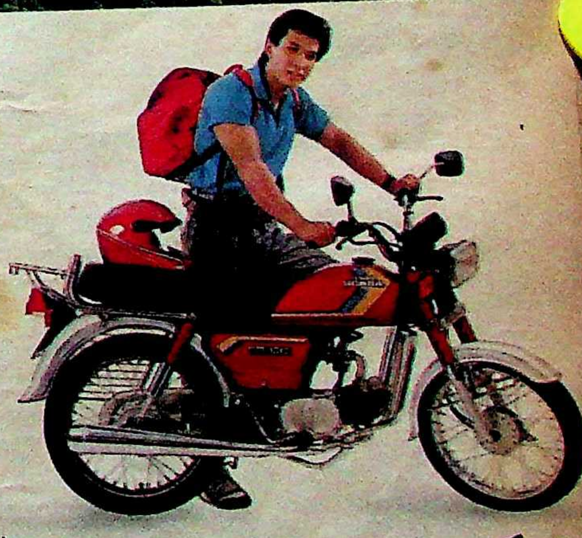

HERO HONDA

आपका शानदार हमसफ़र!

*40 कि.मी. प्रति घंटा और 130 किलो भार सहित.

HTA 63-

ब्रिटेन

राजघराने के प्रेम प्रसंगों का भंडाफोड़

अजब हाल है दुनिया का। कहने को सभी इस बात को मानते हैं कि गलती इंसान से ही होती है, किंतु जब बारी गलती को माफ करने की आती है, तो लोग बगलें झांकने लगते हैं। यही नहीं, हालत तो यह है कि यदि किसी राजघराने से संबद्ध किसी गलती का सुराग जनता को मिल जाये तब तो ऐसा हंगामा खड़ा होता है मानो शाही परिवार से भूल क्या हो गयी उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हाल में ब्रिटिश राजघराने को कुछ इसी तरह की मुसीबत से दो-चार होना पड़ा है।

'सन' का करिश्मा : असल में हुआ यह कि न जाने कैसे और किसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ के घुड़सवार टिमोथी लारेंस द्वारा राजकुमारी एन को लिखे गये चार प्रेम-पत्र बकिंघम पैलेस से उठकर 'द सन' पत्रिका के दफ्तर पहुंच गये। जाहिर है, जिस पत्रिका को हर समय माहौल को गर्माने के लिए सनसनीखेज खबरों की जरूरत रहती है, उसके लिए टिमोथी लारेंस के प्रेम-पत्र बेशकीमती थे। बस फिर क्या था ? आननफानन कथा तैयार हुई। राजकुमारी एन के पति मार्क फिलिप्स के प्रेम संबंधों की बखिया उधेड़ते हुए राजकुमारी के प्रेम प्रसंग का राजफाश कर दिया गया। शुरू में तो इंग्लैंडवासियों ने 'द सन' में प्रकाशित कथा पर इतना ध्यान नहीं दिया, किंतु जब पत्रिका की ओर से यह धमकी दी गयी कि उसे पत्र लिखनेवाले प्रेमी का नाम भी पता है, तो बकिंघम पैलेस ने चुप बैठना उचित न समझा। नतीजतन मजबूर होकर बकिंघम पैलेस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि पत्र किसी और ने नहीं, बल्कि टिमोथी लारेंस ने ही लिखे थे। इस ऐलान ने इंग्लैंडवासियों को सकते में डाल दिया। क्योंकि राजघराने में जो कुछ हो रहा था वह घराने की बर्बादी का संकेत था। दूसरी तरफ राजघराने से जुड़े इस प्रकरण के दूसरे पात्र थे मार्क फिलिप्स जिनके अनगिनत प्रेमसंबंधों में पामेला बोर्डेस का नाम भी शामिल है जिसने हाल में ब्रिटेन में तहलका मचा दिया था।

राज-राज न रहा : राजकुमारी एन

उल्लेखनीय है कि अप्रैल १९८८ में मेजर हग के गायब होने के बाद महारानी की सेवा में आये खूबसूरत टिमोथी लारेंस का काम महारानी की यात्राओं के समय उनकी सुरक्षा करना है। लेकिन टिमोथी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी पूरी करने में यकीन नहीं रखता। खबर तो यहां तक है कि फरवरी में जब राजकुमार चार्ल्स अमरीका गये हुए थे, तो टिमोथी उनकी पत्नी राजकुमारी डायना को मेफेयर रेस्तरां में भोजन कराने ले गया था।

घुड़सवार की जुर्रत : हालांकि टिमोथी बहुत ही खामोश और अलग-थलग रहनेवाला व्यक्ति है, किंतु राजकुमारी एन से अपने प्रेम के कारण उसे बदनामी उठानी पड़ी है। उसके सहपाठियों का कहना है कि लारेंस जिस बात की कसम खा लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। लारेंस के मित्र यह संदेह व्यक्त करते हैं कि संभव है बकिंघम पैलेस में सेवा करने के पीछे उसका लक्ष्य एन से रिश्ता बनाना रहा हो।

बहरहाल, जब लारेंस अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में मसरुफ था तब एन के पति मार्क फिलिप्स २७ वर्षीया काल गर्ल पामेला बोर्डेस के साथ रंगरेलियां मनाने में व्यस्त थे। बकिंघम पैलेस के सूत्रों का कहना है कि पामेला को फिलिप्स के संरक्षक ने गैटकोबे पार्क में बुलाया था। जबकि फिलिप्स का कहना है, "मैंने उसे (पामेला बोर्डेस) २०, ३० या ४० लोगों के साथ सभा-सोसाइटियों में ही देखा है। उसने कभी भी मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा।"

पति-पत्नी में बढ़ती दूरी : वैसे जानकार सूत्रों का कहना है कि राजकुमारी एन और मार्क फिलिप्स कुछ वर्षों से एक-दूसरे से कटते जा रहे हैं। इस दूरी का एकमात्र कारण उनका अलग-अलग 'कैरियर' है जो उनके बीच के फासले को और बढ़ा रहा है। वे साल में छह महीने से अधिक समय तक अलग ही रहते हैं। फिलिप्स घुड़सवारी में वक्त गुजारते हैं, जबकि एन सरकारी कामकाज निबटाने में व्यस्त रहती हैं। शादी के १५ साल बाद इन दोनों ने यह संकेत दिया कि वे एक दूसरे से ऊब चुके हैं। लेकिन उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं था कि उनके ही किसी विश्वासपात्र के चलते यह सारा किस्सा जगजाहिर हो जायेगा। 'द सन' ने भी पत्र मिलने के स्रोत का जिक्र किये बिना ही एन के पत्रों के बारे में खबर छापी है। उसने पत्र में लिखी बातें नहीं छापीं। बाद में ये पत्र स्काटलैंड पुलिस को इस हिदायत के साथ सौंप दिये गये कि वह पत्र लिखनेवाले का पता लगाये।

जहां तक राजकुमारी एन की बात है वह सदा से राज परिवार के अन्य लोगों से बिलकुल अलग तरह का जीवन व्यतीत करती आयी हैं। वे डायना जैसी खूबसूरत और खास तौर-तरीके से जीनेवाली महिला नहीं हैं। फिर भी इंग्लैंड के लोगों को एन की जीवन शैली पर आपत्ति नहीं है। एन पहले कई बार कह चुकी हैं कि सदा सफेद पोशाक में रहना और सर पर मुकुट लगाये रखना उनके बस में नहीं। हां, सरकारी काम निबटाने में वे पूरी ईमानदारी बरतती हैं। १९७० से एन 'सेव चिल्ड्रेन फंड' (बाल रक्षा कोष) की अध्यक्ष हैं। वे ऐसी अन्य ७५ संस्थाओं

का भी काम देखती हैं और प्रति माह कम-से-कम ५० प्रतिनिधियों से मिलती हैं। जब राजकुमारी एन अफ्रीका गयी थीं, तो रेलगाड़ी से यात्रा करके, तंबू में सोकर और गरीबों के साथ घुलमिलकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। मच्छरों, बिच्छुओं और सांपों से भरा तंजानिया हो, हांगकांग हो, कनाडा या अमरीका, वे कहीं भी बेधड़क जाने को तैयार रहती हैं।

एन की मजबूरी : चूंकि एन स्काटलैंड रग्बी यूनियन की प्रमुख हैं इसलिए फ्रांस-स्काटलैंड रग्बी मैच के समय वे जरूर पेरिस में मौजूद रहती हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वे रोज सुबह पांच बजे उठती हैं। अपनी तरह की जिंदगी में वे इतनी मसरुफ रहती हैं कि उनके पास मार्क फिलिप्स के लिए वक्त नहीं बचता। फिर फिलिप्स के पास भी तो पत्नी के लिए वक्त नहीं है। यही कारण है कि दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। मजे की बात तो यह है कि घोड़ों के प्रति जिस लगाव के कारण दोनों एक दूसरे के करीब आये थे, उसका भी असर अब नहीं नजर आता।

हालांकि एन और फिलिप्स इस साल (८९) शरतकालीन खेलों के दौरान साथ में पेरिस गये थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर 'स्कीइंग' की। शादी की १५वीं सालगिरह पर भी दोनों साथ नहीं रहे। उस वक्त फिलिप्स पुरुषों के लिए बनी एक नयी पोशाक को लोकप्रिय बनाने के लिए आस्ट्रेलिया चले गये थे। यही नहीं, पिछले साल भी शादी की सालगिरह पर राजकुमारी एन नेपाल में अकेली ही थीं। जिन लोगों ने दोनों को कभी साथ में देखा है उनका कहना है कि दोनों जब साथ भी होते हैं, तो गुमसुम ही रहते हैं। सियोल ओलंपिक में भी दोनों पहुंचे अवश्य थे, पर वहां पहुंचने के बाद एक बार भी उनकी एक दूसरे से भेंट नहीं हुई थी।

पति के संबंधों का भंडाफोड़ : उल्लेखनीय है कि 'प्रेम-पत्रों' का भंडाफोड़ होने से दो हफ्ते पहले फिलिप्स और पामेला के संबंधों ने काफी हायतौबा मचा रखी थी। खबरों में कहा जा रहा था कि फिलिप्स ने पामेला बोर्डेस से रिश्ते बनाये और उसे घुड़सवारी सिखायी। इस रहस्योद्घाटन के बाद ही पामेला ने यह दावा किया था कि उसके पास ऐसे रहस्य हैं जिनका यदि उद्घाटन कर दिया जाये, तो ब्रिटिश सरकार गिर जायेगी। इस खबर को सुनते ही

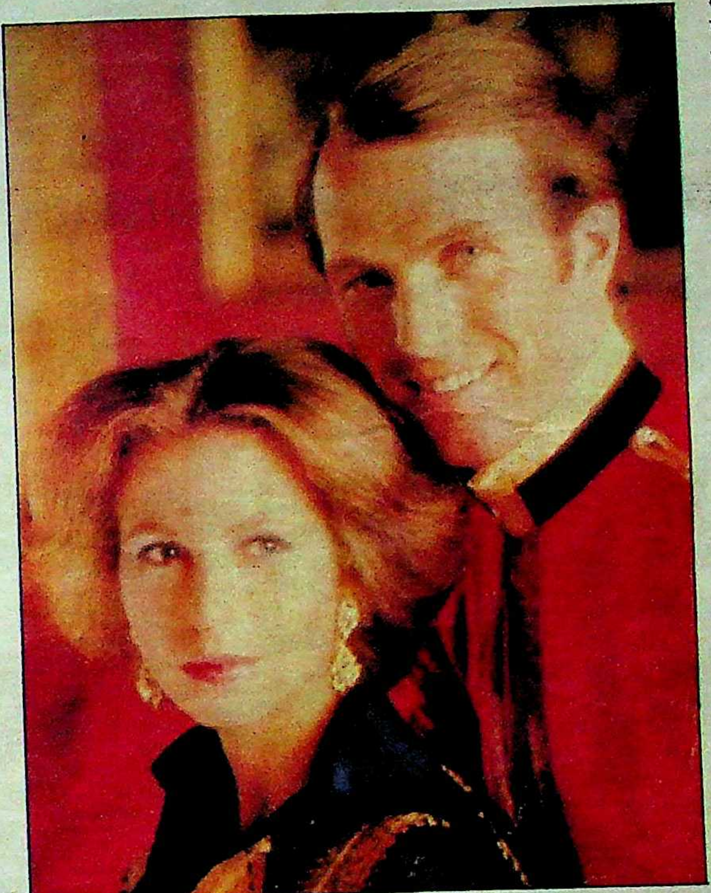

गलती का अहसास : राजकुमारी एन और मार्क फिलिप्स

एन जर्मनी का अपना दौरा अधूरा छोड़कर इंग्लैंड आ गयी थीं। एन का खयाल था कि इस मुद्दे पर फिलिप्स विस्तृत सफाई देंगे। लेकिन फिलिप्स ने यह कहकर मामला आया-गया कर दिया कि पामेला घोड़ों पर आयोजित सेमिनार में बुलायी गयी थी जहां उससे उनकी मुलाकात हुई थी। फिलिप्स ने यह भी बताया कि उसने उनके साथ थोड़ी शराब पी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पामेला में उसकी कोई दिलचस्पी थी। फिलिप्स पामेला से अपने संबंधों की सफाई पेश करने में मसरुफ थे कि तभी 'द सन' ने टिमोथी लारेंस द्वारा एन को लिखे प्रेम-पत्रों की खबर छाप दी। नतीजतन फिलिप्स के संबंधों को लेकर जो माहौल बना था वह दब गया और लारेंस के प्रेम-पत्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया।

टिमोथी को करीब से जाननेवालों का कहना है कि टिमोथी अपने शरीर को चुस्तदुरुस्त रखने पर बहुत ध्यान देता है। वह एकदम नपा-तुला भोजन करता है और इतना अधिक व्यायाम करता है कि अपने को लगानेवाला खिलाड़ी भी शरमा जाये। यही नहीं, टिमोथी को घोड़ों से बहुत प्रेम है। बकिंघम पैलेस में सेवा का अवसर मिलने पर वह काफी खुश था, क्योंकि वह महारानी के साथ हर जगह जाने लगा था। देखते-ही-देखते अपने मृदुल स्वभाव के कारण वह राज परिवार के हर सदस्य का दोस्त हो गया था तथा राज परिवार के लोग उसकी काफी इज्जत और उस पर भरोसा करते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि दिल पर किसी का काबू नहीं चलता वैसे ही कुछ टिमोथी के साथ हुआ। न जाने क्यों उसे एन से प्रेम हो गया और उसे व्यक्त करने के लिए उसने एन को पत्र लिख दिये।

हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एन के लिए इन पत्रों का कोई खास महत्व नहीं था इसीलिए वे उन्हें अन्य सरकारी कागजातों के साथ मेज पर ही रखकर भूल गयी थीं।

बहरहाल, सचाई जो भी हो, लेकिन राजकुमारी एन और मार्क फिलिप्स के बीच बढ़ती दूरी से इनकार नहीं किया जा सकता। संभव है पति-पत्नी के बीच बढ़ते इस फासले को देखकर ही टिमोथी लारेंस ने एन से संबंध बनाने को सोचा हो।

पुलिस विभाग की भूमिका : अच्छा तो यह हुआ कि 'द सन' द्वारा स्काटलैंड यार्ड के सुपुर्द किये हुए पत्रों पर पुलिस विभाग ने ज्यादा हो-हल्ला नहीं किया और मामले को दबा दिया गया। क्योंकि अगर पुलिस विभाग ने पत्रों को आधार बनाकर तिल से ताड़ बनाने की कोशिश की होती, तो टिमोथी लारेंस के पत्र एन और फिलिप्स को तलाक की नौबत तक पहुंचा देते और ब्रिटिश राजघराने पर एक नयी मुसीबत आ पड़ती। जाहिर है, महारानी एलिजाबेथ के पास दुखों की कमी नहीं है। यदि एन का तलाक हो जाता, तो शायद वे इस दुख को सहन न कर पातीं और टूट जातीं। क्योंकि एंडी की शाहखर्ची, राजकुमार चार्ल्स के इतालवी राजकुमारी से प्रेम और एडवर्ड की जरूरत से ज्यादा आकांक्षाओं से वे पहले ही निढाल हो चुकी हैं।

अंजाम : हाल में एक खबर में यह बताया गया है कि अक्तूबर के अंत में टिमोथी लारेंस की सेवा का करार समाप्त हो रहा है। अब देखना यह है कि टिमोथी पुनः सेवा करने के लिए करार पर हस्ताक्षर करता है या नहीं?

बहरहाल, बकिंघम पैलेस के सूत्रों का कहना है कि राजघराने की बदनामी ने पति-पत्नी के बीच बढ़ते फासले को घटाने में मदद की है। टिमोथी के पत्रों के उद्घाटन के बाद एन ने फिलिप्स को समय देना शुरू कर दिया है और फिलिप्स भी एन की तरफ झुक रहे हैं। लगता है, पति-पत्नी को अपनी गलती का अहसास हो गया है। ऐसे में इंग्लैंडवासियों को चाहिए कि राजघराने की गलतियों को दोहराने के बजाय उन्हें भूलने का प्रयास करें।

◆

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ से.मि. एफ.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे की टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली खूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?

ओनिडा २१
पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

क्या नए
ओनिडा पर प्रतिबंध
लगाया जाए?

श्रीलंका

शांति सेना से अशांति का खतरा ?

श्रीलंका के राष्ट्रपति रर्णसिंघे प्रेमदास की शांति सेना वापस लौटाने के लिए भारत को दी गयी धमकी ने देश में बावेला खड़ा कर दिया है। जहां विपक्षी दिग्गज ऐसे में शांति सेना की घर वापसी के खैरख्वाह हैं, वहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस बात पर अड़े हैं कि 'मिशन' पूरा होने से पहले शांति सेना वापस नहीं बुलायी जायेगी। आखिर किन खतरों को मद्देनजर रखकर राजीव गांधी अपना फैसला नहीं बदल रहे हैं और इस ज़िद का अंजाम क्या होगा ?

छाया: पाना इंडिया

मिशन की सनद: प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए

श्रीलंका के राष्ट्रपति रर्णसिंघे प्रेमदास ने अचानक ऐसा रुख बदला है कि लगता है कि भारत-श्रीलंका संबंध खराब होकर ही रहेंगे। हाल में उन्होंने भारत को धमकी दी है कि यदि भारत ने २९ जुलाई तक शांति सेना श्रीलंका से वापस नहीं बुलायी, तो शांति सेना के जवानों को बैरकों में बंद कर दिया जायेगा। यही नहीं, अपनी धमकी को वजनदार बनाने के लिए राष्ट्रपति प्रेमदास ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक भारत श्रीलंका से अपनी सेना नहीं हटायेगा तब तक श्रीलंका दक्षेस सम्मेलनों में भाग नहीं लेगा। जाहिर है, प्रेमदास के इस रुख को देखकर राजनीति की मामूली समझ रखनेवाला व्यक्ति भी इतना समझ सकता है कि प्रेमदास ने शांति सेना को निश्चित समय में श्रीलंका से हटाये जाने का ऐलान करके भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। यही नहीं, राष्ट्रपति प्रेमदास ने शांति सेना को हटवाने का जो रवैया अपनाया है उससे तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि भारत दक्षिण एशियाई देशों से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता और उनके बीच अपनी गौरवान्वित स्थिति को कायम रखना चाहता है, तो उसे श्रीलंका से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। किंतु मामला कुछ उलटा ही है। राष्ट्रपति प्रेमदास की धमकी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंभीरता से लिया तो है, किंतु शांति सेना को प्रेमदास के आग्रह पर शीघ्र हटा लेने के लिए वे राजी नहीं दिखायी पड़ते। बल्कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो कुछ ऐसा रुख अपनाया है जिससे लगता है कि उन्हें अपने पड़ोसी तथा दक्षेस सदस्य देश श्रीलंका की परवाह ही नहीं। जब इस संबंध में 'माया' ने एक विपक्षी नेता से टिप्पणी करने को कहा, तो वे बोले, "लगता है कि जिद पर अड़े प्रधानमंत्री राजीव गांधी सेना को श्रीलंका से तभी बुलायेंगे जब भारत का मुंह पूरी दुनिया के सामने काला हो चुका होगा।" यही नहीं, भाजपा नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने तो शांति सेना को स्वदेश बुलाने की मांग करते हुए 'माया' से कहा, "श्रीलंका से अपनी सेना न लौटाने के परिणामों को सोचकर मैं कांपने लगता हूं।" कुछ इसी तरह का

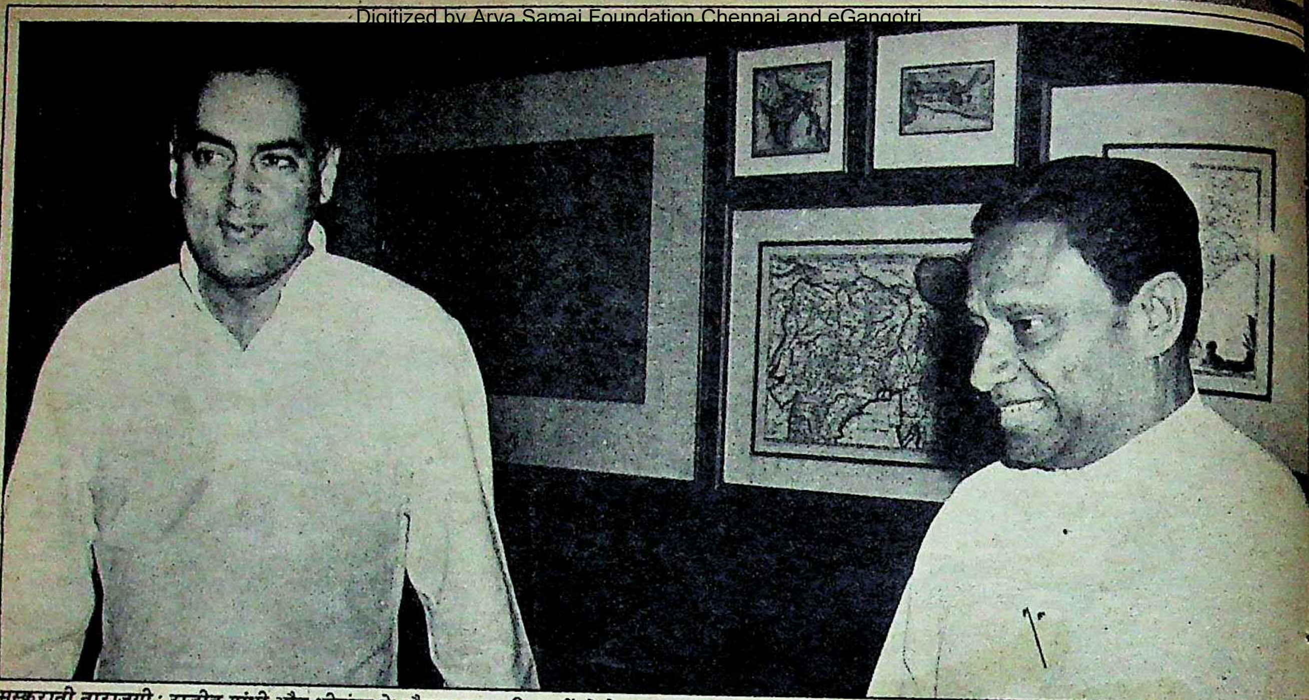

मुस्कुराती नाराजगी : राजीव गांधी और श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास

छाया : पाना इंडि

नजरिया जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथप्रताप सिंह का भी है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री से यह बताने का आग्रह किया है कि आखिर श्रीलंका में इतना खून और धन बहाने से देश को क्या लाभ हुआ?

प्रधानमंत्री की जिद : बहरहाल, जैसाकि कहावत है कि जितने मुंह उतनी ही बातें, कुछ इसी तरह का माहौल राष्ट्रपति प्रेमदास की धमकी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जिद को लेकर, बना है। हालांकि वामपंथी दलों ने भी श्रीलंका से शांति सेना को सादर वापस बुलाने की मांग की है, किंतु प्रधानमंत्री का कहना है, "जब तक शांति सेना का मिशन पूरा नहीं हो जाता, वह श्रीलंका में ही रहेगी।" राजीव गांधी ने प्रेमदास की धमकी का जवाब देते हुए कहा, "भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत हमारे ऊपर तमिलों की सुरक्षा तथा श्रीलंका में शांति की स्थापना का दायित्व है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही सेना वापस बुलायेंगे।" यही नहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान तो राजीव गांधी यह भी कहते नहीं चूके कि भारत किसी तरह के दबाव में आकर अपनी सेना वापस नहीं बुलायेगा।

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने धमकी भरा लहजा अपनाने से पूर्व भी सार्वजनिक रूप से कई बार शांति सेना को लौटाने की मांग भारत से की थी। जहां तक अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात है, उनके अनुसार तो यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति के आग्रह पर भारत अपनी सेना नहीं लौटाता, तो उसे आक्रमणकारी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय सेना का श्रीलंका के राष्ट्रपति की इच्छा के बिना अब वहां रहना श्रीलंका की संप्रभुता पर हमला करार दिया जायेगा।

भारत की दलील : दूसरी ओर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दलील है कि श्रीलंका के साथ हुए समझौते के अंतर्गत शांति सेना एक निश्चित कार्य के लिए श्रीलंका गयी थी और उस कार्य को पूरा किये बगैर उसे लौटाना सेना और समझौते की विफलता होगी। प्रधानमंत्री यह नहीं चाहते कि समझौते की विफलता को आधार बनाकर उनके कदम का मजाक उड़ाया जाये। फिर भारतीय सेना समझौते के अंतर्गत तमिलों की सुरक्षा का दायित्व पूरा करने के लिए श्रीलंका में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और १,००० से अधिक सैनिकों का बलिदान दे चुकी है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्ररपति की धमकी पर ध्यान देकर समझौते को खुद विफल करना कायरता के सिवा और क्या है?

शांति सेना को श्रीलंका से हटाने के मसले पर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस पर राजनीतिक पर्यवेक्षक भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं पेश कर रहे हैं। कुछ का तो मानना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सेना को हटाने की बात कहकर भारत को कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि जब भारत ने सेना श्रीलंका भेजी थी, तो उस समय पाकिस्तान ने भारत द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण का आरोप लगाया था। उत्तर में भारत ने कहा था कि सेना श्रीलंका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर गयी है और श्रीलंका के राष्ट्रपति जब चाहेंगे, उसे लौटने को कह सकते हैं। उसी बात को दोहराते हुए राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास ने कहा, "भारत ने हमें बार-बार आश्वासन दिया है कि जब भी श्रीलंका के राष्ट्रपति चाहेंगे, सेना लौटा ली जायेगी।" पर्यवेक्षकों को इस बात पर आश्चर्य है कि जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की ही पेशकश के तहत सेना हटाने की खुलेआम मांग की है, तो भारत के हिचकिचाने की वजह समझ में नहीं आती।

तमिल हित सर्वोपरि : इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं कुछ दिग्गज नेता जिनका मानना है कि शांति सेना की वापसी का मुद्दा आगामी चुनावों से जुड़ा है। यदि प्रधानमंत्री सेना लौटा लेते हैं, तो यह भारत-श्रीलंका समझौते की असफलता मानी जायेगी और यह चुनावों में राजीव गांधी को भारी पड़ सकता है। हालांकि श्रीलंका में तमिल हितों का खयाल रखनेवाले राजनीतिक गुट का मानना है कि भारत की हिचकिचाहट का मुख्य कारण यह डर है कि शांति सेना के लौटते ही 'लिट्टे' दूसरे तमिल ग्रुपों पर हावी हो जायेगा तथा मारकाट का एक नया दौर आरंभ हो जायेगा। यही नहीं, संभावना तो यह भी है कि लिट्टे और अन्य तमिल गुटों के बीच तथा तमिल गुटों और सिंहली उग्रवादियों के बीच जो घमासान शुरू होगा, उस पर नियंत्रण मुश्किल हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उत्तर और पूर्वी श्रीलंका के जो तमिल भारत को अपना हितैषी और सुरक्षा कवच मानते हैं, वे शरण के लिए भारत की ओर दौड़ेंगे। चूंकि श्रीलंका में रहनेवाले तमिलों के प्रति तमिलनाडु की जनता पहले से ही संवेदनशील रही है, इसलिए ऐसी स्थिति बनने पर तमिलनाडु में माहौल बिगड़ सकता है। भारत को यह भी आशंका है कि शांति सेना के वापस होते ही श्रीलंका में एक बार फिर स्वतंत्र तमिल राष्ट्र 'ऐलम' की मांग सिर उठायेगी जो भारतीय हितों के लिए घातक होगी। इस तरह की संभावनाओं और खतरों का जिक्र करते हुए राजनीतिक श्रीलंका के बट्टिकोलोआ जिले के सांसद सैम थम्दीमुट्टू के हाल के बयान का उल्लेख करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, "तमिलों को शांति व

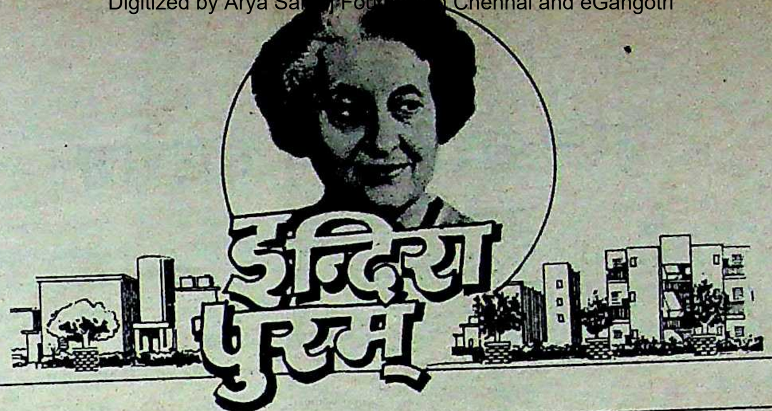

उनकी पुण्य स्मृति को मूर्त्त रूप प्रदान करते हुए

दिल्ली के निकट, गाज़ियाबाद में भूखण्डों, आवासों तथा अपार्टमेन्ट्स का स्ववित्त पोषित व किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत पंजीकरण

इन्दिरा अपार्टमेन्ट्स
(किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत)

क्रम सं.	विवरण	कवर्ड एरिया (वर्ग मी. में) (आच्छादित एरिया सहित)	अपार्टमेन्ट्स का मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (10%+ रु. 20/-)
1.	एक कमरा, बाथ, टायलेट, किचन एवं बॉलकोनी	33.61	1,60,000/-	16,020/-
2.	एक कमरा, ड्राईंग/डायनिंगरूम, किचन, बाथ, टायलेट एवं बॉलकोनी	68.68	2,75,000/-	27,520/-
3.	दो कमरे, ड्राईंग/डायनिंग, किचन, बॉलकोनी, बाथ	70.27	3,60,000/-	36,020/-
कम्पोज़िट :– (डिलक्स टाईप)				
4.	दो कमरे का अपार्टमेन्ट (दो कमरे, ड्राईंग/डायनिंग व सुविधायें)	101.3	4,50,000/-	45,020/-
5.	तीन कमरे का अपार्टमेन्ट (दो कमरे, ड्राईंग/डायनिंग, लौंज व सुविधायें)	134.9	5,80,000/-	58,020/-
6.	चार कमरे का अपार्टमेन्ट (तीन कमरे, ड्राईंग/डायनिंग लौंज व सुविधायें)	159.17	7,25,000/-	72,520/-

भुगतान अवधि :–

12 से 15 वर्षों में
40% तीन वर्ष में, शेष 60% 12 से 15 वर्षों की छःमाही किश्तों में ब्याज सहित जो ऋण देने वाली संस्था पर निर्भर करेगा।

आवेदन कैसे करें :– पंजीकरण पुस्तिका रु. 25/- (रु. पच्चीस) का भुगतान करके ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की निम्नलिखित शाखाओं से तथा रु. 35/-(रु. पैंतीस) का मनीऑर्डर ओ.बी.सी., एस.आई-9, शास्त्रीनगर, रजापुर शाखा, गाजियाबाद के नाम करके डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है:

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

गाज़ियाबाद-एस.आई.-9, शास्त्रीनगर, रजापुर ● गाईट गंज कन्या वैदिक स्कूल के सामने ● नेहरू नगर, होली चाइल्ड स्कूल के सामने। नई दिल्ली-ए-30-33 प्रथम तल, कनॉट प्लेस ● प्रिया सिनेमा कॉम्प्लैक्स, प्रथम तल, बसन्त लोक। दिल्ली-73-74-75 व 60/1, मुन्दर कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, चावड़ी बाज़ार, ● एफ-6/7 विजय चौक, लक्ष्मी नगर। बम्बई-1 डॉ. बी.बी. गाँधी मार्ग फोर्ट। मद्रास-769, अन्ना सलाई, माउन्ट रोड। कलकत्ता-2, कॅमेट स्ट्रीट, ● पार्क स्ट्रीट। अमृतसर-सिविल लाइन्स, बवीन्स रोड। लुधियाना-चौड़ा बाजार। चण्डीगढ़-सेक्टर-17-बी। मेरठ-सदर बाजार। लखनऊ-94, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज। कानपुर-दि माल।

भूखण्डों का विवरण (फ़ेज़-I)

श्रेणी	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित संख्या	मूल्य (प्रति वर्ग मी.)	पंजीकरण धनराशि (10%+रु. 20/-)
ए	350	200	1200/-	42,020/-
बी	250	300	1150/-	28,770/-
सी	200	300	1100/-	22,020/-
डी	112	400	1000/-	11,220/-
ई	90	500	850/-	7,670/-

भुगतान अवधि :
पंजीकरण के समय 10% धनराशि, 15% आरक्षण के समय तथा शेष तीन साल में छःमाही किश्तों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से

मुख्य आकर्षण :–

- भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है एवं यह प्राधिकरण के कब्जे में है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित इंदिरापुरम् क्षेत्र दिल्ली के विकसित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कार के माध्यम से दिल्ली के व्यावसायिक क्षेत्र तक की दूरी मात्र 15 मिनट है।

ई.डब्ल्यू.एस. भवन (किराया क्रय पद्धति पर)

श्रेणी	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण राशि	कवर्ड एरिया (वर्ग मी. में) आच्छादित एरिया सहित	विवरण	भवनों की सं.
ई.डब्ल्यू.एस. चार मंज़िले	34,000/-	3,420/-	21.00	एक कमरा, किचन, बाथ, टायलेट	5,000

KRITI

भुगतान अवधि :– 15 वर्षों में
40% तीन साल में, शेष 60% 15 वर्ष की छःमाही किश्तों में ब्याज सहित जो ऋण देने वाली संस्था पर निर्भर करेगा।

दिल्ली
दिल्ली से
इन्दिरापुरम

पंजीकरण अवधि 27.6.89 से 31.7.89

अनिल कुमार शर्मा
सचिव

प्रभुनाथ मिश्र
उपाध्यक्ष

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाज़ियाबाद

एक सुन्दर शहर – हमारा संकल्प

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीज

वर्ष १९६९ में मात्र एक योजना का बिरवा, पौधा अब २० वर्षों के बाद बरगद का सा मजबूत वृक्ष हो चुका है जिसकी सात प्रमुख शाखाएं योजनाएं (गंगा-कावेरी, धनलक्ष्मी, संगम, आकांक्षा, जनता, रोहिणी तथा यू०पी० रैफल पूरे भारत वर्ष में फैल रही है और यह व्यापक लोकहित तथा लोक कल्याण की ही शाखाएं हैं।

उत्तर प्रदेश लाटरी निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों को लाभ पहुंचाने के पवित्र उद्देश्यों से संचालित है और इसी विलक्षण विशेषता के कारण यह करोड़ों लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। यह लाटरी सभी के लिए सभी के हित में अर्पित है क्योंकि अपरिहार्य खर्च के बाद अर्जित आय का लाभ कृपालु क्रेताओं, विजेताओं तथा अन्य सभी तक पहुंचाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप अब तक लगभग २२ करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि बीमार, असाध्य लोगों के इलाज तथा जीवनार्थ अच्छे उपकरण, यंत्र, चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा की दिशा में सुलभ कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश लाटरीज दुख में, बीमारी में, अवाम, नागरिक के साथ है, उनकी तीमारदारी में इलाज में भी उनके साथ है। दुख में जो साथ हो, जो साथ दें, वही मित्र है, अपना है और यह कर्त्तव्य, यह अन्जाम उत्तर प्रदेश लाटरीज विगत २० वर्षों से निभा रहे हैं।

इतना ही नहीं, बल्कि असंख्य घरों परिवारों में पुरस्कारों की राशि से खुशी और समृद्धि भी पहुंची है और नित्यप्रति पहुंच रही है। इस दिशा में अब तक लगभग दो सौ करोड़ रुपया पुरस्कार तथा बोनस आदि के रूप में दिया जा चुका है, और मात्र वित्तीय वर्ष १९८८-८९ में यह राशि लगभग ८७ करोड़ है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के पुनीत अवसर पर हमारा यह प्रयास है कि अनगिनत बच्चों के चेहरों पर परिवारों पर और मुस्कराहट आये, भारत के बच्चों का बचपन गुलाब की तरह खिले और महके इस दिशा में अनवरत प्रयास जारी है।

उत्तर प्रदेश शासन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से दिसम्बर, १९६८ में उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी योजना का शुभारम्भ किया।

उ०प्र० लाटरी निदेशालय ने जन-भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष १९७७-७८ में जनता लाटरी योजना तथा १९८२-८३ में संगम लाटरी योजना का भी प्रारम्भ किया इन योजनाओं का भी आशानुसार बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई और शनैः-शनैः उ०प्र० लाटरी योजना का एक अच्छा बाजार पूरे भारत वर्ष में स्थापित होने लगा।

विक्री प्राप्तियों के उपयोग (यूटीलाइजेशन आफ प्रोसीड्स) नियमावली १९६९ के अन्तर्गत लाटरी टिकटों की शुद्ध प्राप्तियों को वर्षानुवर्ष चिकित्सा निधि को हस्तान्तरित किया जाता रहा है ताकि प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं में सुचारु और विस्तार हेतु सम्बन्धित अस्पतालों तथा अन्य को यथोचित धनराशियां उपलब्ध हो सकें।

समूचे भारतवर्ष में फैले हुए लाखों लाटरी विक्रेताओं, सेलर्स तथा क्रेताओं के सहयोग से निदेशालय अब तक लगभग २२ करोड़ रुपये की धनराशि हास्पिटल फण्ड कमेटी को समर्पित कर चुका है जिसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अंग प्रदान करने में सहायता मिली है और यह प्रक्रिया अब भी अनवरत रूप से जारी है।

लाटरी निदेशालय की ओर से चलाई जा रही लाटरी योजनाओं का संचालन करने के लिए देश भर में स्टाकिस्ट नियुक्त किये जाते हैं और एजेन्ट तथा सेलर्स के माध्यम से विक्री होती है। इस दिशा में असंख्य बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सके इस ओर निदेशालय का सतत् प्रयास रहता है। साथ ही अवकाश प्राप्त सेनानियों, गणमान्य नागरिकों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को इस कल्याणकारी कार्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिससे इन योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जारी योजनाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों को लाभ पहुंचा तथा पहुंच रहा है।

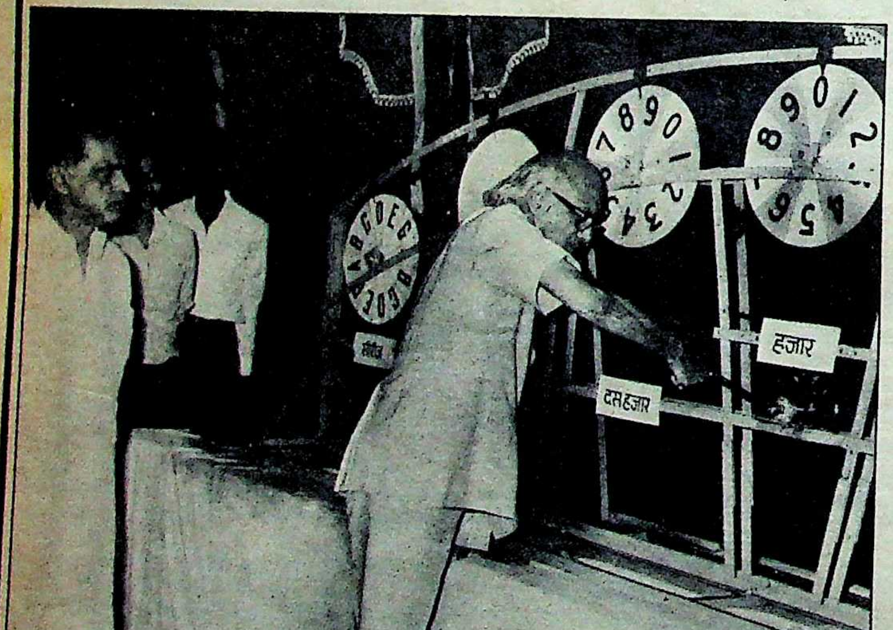

निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य लाटरीज,
कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड,
इंदिरानगर, लखनऊ।

विज्ञापन

सुरक्षा प्रदान करना भारत की जिम्मेदारी है और यदि तमिलों के साथ श्रीलंका सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, तो श्रीलंका का विभाजन हो सकता है।" कुछ इसी तरह का नजरिया उत्तर-पूर्वी तमिल प्रांत के भारत-समर्थक मुख्यमंत्री वरदराज पेरुमल ने भी राष्ट्रपति प्रेमदास द्वारा शांति सेना लौटाने की मांग के विरोध में आयोजित एक जनसभा में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यदि दोनों प्रमुख भाषाई समूहों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया और इसके चलते देश-विभाजित हुआ, तो इसकी दोषी श्रीलंका सरकार होगी।"

विभाजन का खतरा: दरअसल, श्रीलंका के विभाजन की खुलेआम बातों ने भारत को इसलिए भयभीत कर दिया है, क्योंकि इसका तमिलनाडु पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फिर यदि भारत ने किसी भी तरह से श्रीलंका के विभाजन में मदद की, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि मटियामेट हो जायेगी। किंतु मसले के इस अहम पहलू पर ध्यान दिये बिना ही जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे २९ जुलाई-शांति सेना के श्रीलंका पहुंचने की दूसरी वर्षगांठ-को स्वतंत्र तमिल राष्ट्र 'एलम' की घोषणा कर दें। डा० स्वामी ने कहा, "श्रीलंका की अखंडता को बनाये रखने के लिए भारतीय शांति सेना के बलिदानों के प्रति श्रीलंका के राष्ट्रपति की अकृतज्ञता और अहंकार को देखने के बाद सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि तमिल श्रीलंका को खंडित कर दें।"

हालांकि श्रीलंका से भारतीय शांति सेना लौटाने के एक विरोधी ने डा० स्वामी के बयान का जवाब देते हुए कहा, "यदि शांति सेना लौटा ली जाती है, तो डा० स्वामी जैसा कोई तमिल नेता कह सकता है कि श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री की बेरुखी देखने के बाद सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचता कि भारत की अखंडता पर वार किया जाये।" कुछ भी हो इतना तो है कि यह स्थिति भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मुकाबले अधिक संवेदनशील होगी। ऐसे में भारत के पास एकमात्र रास्ता यह होगा कि वह श्रीलंका में सीधा हस्तक्षेप कर तमिलों की मदद करे। एक पर्यवेक्षक के अनुसार ऐसी स्थिति को दावत देने से बेहतर है कि भारत शांति सेना श्रीलंका से लौटाये ही नहीं।

इस बात से कौन वाकिफ नहीं कि जब प्रेमदास प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने भारत-श्रीलंका समझौते का विरोध किया था? यही नहीं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान भी उन्होंने भारत-विरोध को ही अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था और अब वे अपने नजरिये का प्रयोग भारत-विरोधी तमिल गुट 'लिट्टे' और सिंहल उग्रवादी गुट 'जेवीपी' के बीच समझौते के आसार को भुनाने के लिए कर रहे हैं।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार नें सार्वजनिक रूप से ऐसा मंशा जाहिर नहीं किया है। इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है, "भारत सेना लौटायेगा, पर दबाव में आकर नहीं।" दूसरी ओर श्रीलंका के राजनयिक यह मानने को तैयार नहीं कि सेना की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है। उनके अनुसार राष्ट्रपति प्रेमदास ने बहुत मित्रतापूर्ण शब्दों में सेना लौटाने का आग्रह किया है, जो उनका अधिकार है। अपने इस नजरिये को आधार देने के लिए श्रीलंका के राजनयिक राष्ट्रपति प्रेमदास के उस वक्तव्य को दोहराते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, "हम भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को दी गयी मदद कभी नहीं भूलेंगे। कौन नहीं जानता कि श्रीलंका में बुद्ध धर्म भी भारत की ही भेंट है जिसकी श्रीलंका में स्थापना के लिए सम्राट अशोक ने मदद की थी? यही नहीं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के आग्रह पर शांति सेना भेजना भी बहुत बड़ी मदद थी। हमें उम्मीद है कि हमारे आग्रह पर शांति सेना लौटाने की भारतीय कार्यवाही भी मात्र एक रियायत समझी जायेगी।"

प्रेमदास की चाल: दूसरी ओर भारतीय राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति प्रेमदास के उपर्युक्त बयान को मित्रतापूर्ण न बताकर कूटनीतिक चाल कहते हैं। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए वे रणसिंघे प्रेमदास के भारत विरोधी नजरिये की ओर इशारा करते हैं। इस बात से कौन वाकिफ नहीं कि जब प्रेमदास प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने भारत-श्रीलंका समझौते का विरोध किया था? यही नहीं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान भी उन्होंने भारत-विरोध को ही अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था और अब वे अपने नजरिये का प्रयोग भारत-विरोधी तमिल गुट 'लिट्टे' और सिंहल उग्रवादी गुट 'जेवीपी' के बीच समझौते के आसार को भुनाने के लिए कर रहे हैं।

बहरहाल, श्रीलंका से शांति सेना हटाने का मसला दिन-पर-दिन जितना पेंचीदा होता जा रहा है उसे देखकर पड़ोसी देश से संबंध बिगड़ने की आशंका व्यक्त करना अनुचित न होगा। मजे की बात तो यह है कि भारत तो फिर भी असमंजस में पड़कर कुछ कम कड़ुवा बोल रहा है, किंतु श्रीलंका के राजनयिकों की ओर से जिस तरह के वक्तव्यों के बाण छोड़े जा रहे हैं, उन्हें सुन-पढ़ कर तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीलंका सरकार शांति सेना को मुद्दा बनाकर संबंध बिगाड़ने तक की हद को जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा कि भारत श्रीलंका से शांति सेना जरूर लौटायेगा, किंतु उस ताबड़तोड़ ढंग से नहीं जैसा राष्ट्रपति प्रेमदास चाहते हैं, तो प्रेमदास का वक्तव्य काफी गुस्सा दिलानेवाला था। प्रेमदास ने जवाब में कहा था, "ठीक है। २९ जुलाई के बाद भारतीय सेना बैरकों में भेज दी जायेगी।" उल्लेखनीय है कि ताबड़तोड़ ढंग से सेना न हटाने की बात को तर्क देते हुए मई '८९ के अंत में भारत ने कहा था कि ४०,००० सैनिकों को दो माह में वापस बुलाने के लिए उसके पास जहाज नहीं हैं। इस पर श्रीलंका के विदेशमंत्री रंजन बिजेरत्ने, जो श्रीलंका की कैबिनेट के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं, ने भारत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, "यह भी क्या मजाक है? जब हमने उन्हें आमंत्रित किया था, तो वे जितनी तेजी से श्रीलंका आये थे, वह हमें याद है।" यही नहीं, हाल में श्रीलंका के विदेशमंत्री ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, "भारत को चाहिए कि वह भारत-श्रीलंका समझौते की लिपि पुनः पढ़े। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारतीय शांति सेना तभी तक श्रीलंका में रह सकती है जबतक श्रीलंका के राष्ट्रपति चाहेंगे। फिर हमने अपना काम पूरा कर लिया, उन्होंने (भारत ने) अपना मिशन पूरा नहीं किया, तो क्या किया जाये?"

राजनीतिक खिचड़ी: बहरहाल, शांति सेना की वापसी के मसले पर देश के सत्तारूढ़ दल के नेताओं तथा विपक्षी दिग्गजों के बीच जिस तरह की खिचड़ी पक रही है, वह है तो सचमुच किसी बड़े खतरे का संकेत। इस बात में संदेह नहीं कि यदि भारत अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ता, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि दागदार हो जायेगी। किंतु श्रीलंका के राष्ट्रपति का आग्रह मान लेने पर जिन संभावित खतरों की निशानदेही की जा रही है, वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों ही फैसले भारत के लिए नुकसानदेह हैं, तो निर्णय लेना वाकई है तो बड़ी सूझ की बात। फिर हाल में ही मामूली तकरारों के चलते भारत-नेपाल संबंध जिस तरह से बिगड़े, वह भी सबके सामने है। ऐसे में सिर्फ यह राग अलापना की शांति सेना की वापसी आगामी चुनावों में राजीव गांधी का चुनावी मुद्दा होगी, उचित नहीं। सभी को चाहिए कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा रास्ता सुझायें जिससे विश्व में देश का मस्तक भी उठा रहे और देश की अखंडता और एकता में भी दरार न पड़ने पाये। बीच का रास्ता क्या होगा, यह तो नहीं बताया जा सकता, किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि भारत ने भी श्रीलंका की तरह तेवर बनाये रखा, तो बात बनने के बजाय बिगड़ जायेगी क्योंकि बड़े और शक्तिशाली का दायित्व होता है कि वह छोटे और कमजोर के रवैये से उत्तेजित न हो।

—अभय अग्रवाल

अमरीका

आर्थिक प्रतिबंध की धौंसपट्टी

अमरीका ने भारत के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की जो धमकी दी है, उसके पीछे असली मंशा क्या है ?

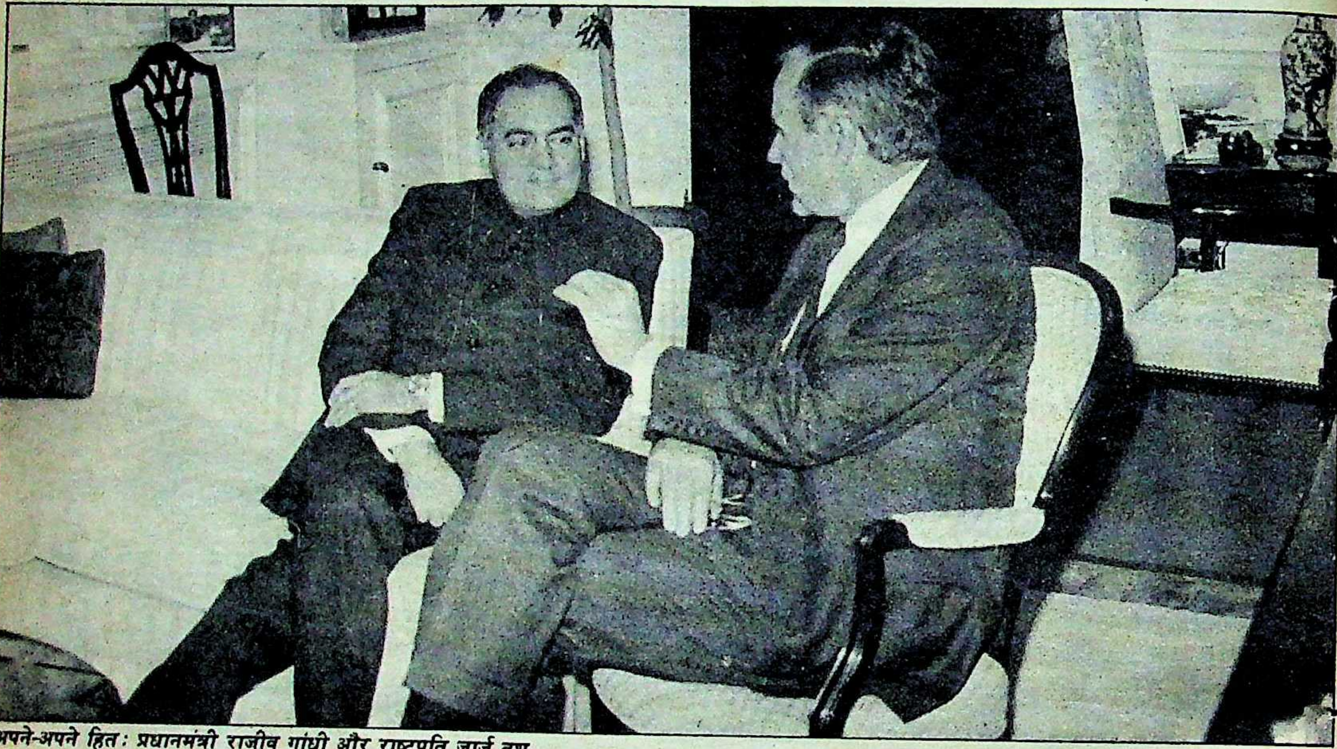

अपने-अपने हित : प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जार्ज बुश

सचमुच अमरीका की नजर फिर गयी है। उसकी वाणिज्य प्रतिनिधि कार्ला हिल्स ने भारत को भी जापान और ब्राजील के साथ उसी सूची में रखा है जिनके खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लग सकता है। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत अपने यहां की आर्थिक नीतियों को नरम बनाकर अमरीकी कंपनियों को यहां आने की अनुमति नहीं देगा, तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगेंगे।

आज अमरीका भारत से आर्थिक संबंधों पर सौदेबाजी करने की बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत अपना २० फीसदी माल वहीं निर्यात करता है। अमरीका यह भी जानता है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का भयंकर अकाल है और भारत अपने इस सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार से रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर अमरीका अपने विदेशी व्यापार का ही भारत को निर्यात करता है। इसलिए भारत कड़ा रुख अपनाकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

लेकिन देश के कर्ताधर्ता अभी तक बहादुरी की मुद्रा ही अपनाये हुए हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा है कि हम किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। वाणिज्यमंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि हम किसी भी दबाव में राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठायेंगे। वित्तमंत्री शंकर राव चाह्वाण ने कहा कि अगर अमरीकी निवेशक भारत में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें यहां के कायदे-कानून मानने होंगे। जिन क्षेत्रों में हमने भारतीय लोगों को

> निश्चित रूप से अमरीकी मंशा को जता देने में कार्ला हिल्स ने सपाट बयानी की, वरना वे इसे एक सैद्धांतिक मुखौटा पहना सकती थीं। अगर भारत सरकार ने उनके 'आदेश' को नहीं माना, तो क्या होगा ? फिक्की के महासचिव पाई पेनांदिकर कहते हैं, "अगले १२ से १८ महीनों तक तो दोनों सरकारें इस मुद्दे पर बातचीत करती रहेंगी। अगर भारत ने अमरीका की इच्छा के अनुसार बदलाव कर दिया, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वे अपनी नीतियों को सही बताती हैं, तो अमरीका बदले की कार्रवाई के तौर पर भारतीय माल पर १०० फीसदी सीमा शुल्क बढ़ा देगा।" पेनांदिकर मानते हैं कि आगामी चुनाव तक अमरीका कुछ नहीं करनेवाला है।

पूंजी निवेश की अनुमति नहीं दी है, उनमें भी विदेशियों द्वारा पूरी तरह स्वतंत्र निवेश संभव नहीं है।

आरोप: कार्ला हिल्स के बयान से तो यही लगता है कि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पक्का पता भी नहीं है। भारत को 'सुपर—३०१' वर्ग में शामिल करने की धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हर प्रकार के नये निवेश और पुराने निवेश को बढ़ाने के लिए हर बार सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। फिर यह अनुमति भी उसी स्थान के लिए दी जाती है, जहां विदेशी निवेश के बिना काम न चले। जिन जगहों में विदेशी पूंजी लगी हो, वहां भी सरकार देसी माल के उपयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह करती है, और उसकी जगह बेहतर क्वालिटी और सस्ती दरवाली विदेशी चीजें आयात करने की अनुमति नहीं देती। कुछ निवेशकों से निर्यात के लक्ष्य पूरे करने को भी कहा जाता है।

कार्ला हिल्स के अनुसार भारत का दूसरा अपराध बीमा के कारोबार में निजी कंपनियों को घुसने की इजाजत नहीं देना है। भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहयोगी बीमा कंपनियां ही सामान्य बीमा करती हैं, जबकि जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार है। उन्होंने कहा कि बीमा बाजार को मुक्त करने से अमरीकी बीमा कंपनियों को भी मौका मिलेगा।

निश्चित रूप से अमरीकी मंशा को जता देने में कार्ला हिल्स ने सपाट बयानी की, वरना वे इसे एक सैद्धांतिक मुखौटा पहना सकती थीं। अगर भारत सरकार ने उनके 'आदेश' को नहीं माना, तो क्या होगा? फिक्की के महासचिव पाई पेनांदिकर कहते हैं, "अगले १२ से १८ महीनों तक तो दोनों सरकारें इस मुद्दे पर बातचीत करती रहेंगी। अगर भारत ने अमरीका की इच्छा के अनुसार बदलाव कर दिया, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वे अपनी नीतियों को सही बताती है, तो अमरीका बदले की कार्रवाई के तौर पर भारतीय माल पर १०० फीसदी सीमा शुल्क बढ़ा देगा।" पेनांदिकर मानते हैं कि आगामी चुनाव तक अमरीका कुछ नहीं करनेवाला है।

लेकिन कार्ला हिल्स ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस सूची में दर्ज सभी व्यापारिक सहयोगी देशों से संबंध रखने के मामलों पर १ नवंबर, १९८९ के पहले विचार करके फैसला किया जायेगा कि उन्हें प्राथमिकता-वाली सूची (प्रायरिटी लिस्ट) में शामिल किया जाये, या नहीं। इस अवधि के बीच में भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है और इस सूची में शामिल होने का मतलब है, बदले की कर्रवाई का शिकार होना।

स्पष्ट है कि अगर भारत वित्तमंत्री शंकर राव चह्वाण के कहे अनुसार झुकने से इनकार कर देता है, तो यह बदनाम ३०१ धारा और पहले भी लागू हो सकती है। अमरीका के अनुसार भारत निम्नलिखित कदम उठाकर अमरीका का कोपभाजन होने से बच सकता है:

- पेटेंट संरक्षण कानून में सुधार
- विदेशी ट्रेड मार्क के इस्तेमाल के खिलाफ प्रावधान हटाना
- सर्विस मार्क का भी पंजीकरण
- प्रसिद्ध मार्कों के संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था
- नकल के खिलाफ बेहतर प्रवर्तन व्यवस्था
- विज्ञान और तकनीकी समझौते से युक्त बौद्धिक संपदा अनुलग्नक तैयार करना और
- बहुपक्षीय बौद्धिक संपदा पर बातचीत में रचनात्मक भागीदारी।

खबर है कि भारत अमरीका के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने से इनकार नहीं करता। साथ ही वित्तमंत्री चह्वाण यह भी कहते हैं कि जब जीवन बीमा के क्षेत्र में हमने किसी देसी कंपनी को आने की अनुमति नहीं दी है और देश की बड़ी कंपनियां भी एकाधिकार कानून के तहत होती हैं, तो अमरीकी कंपनियों के लिए हम कैसे सारे कायदे-कानून खतम कर सकते हैं? एक साक्षात्कार में चह्वाण ने कहा, "क्या वे सभी भारतीयों को बेरोक-टोक अपने यहां आने की अनुमति दे सकते हैं? अगर वे अपने यहां ऐसे प्रतिबंध रख सकते हैं, तो हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऐसे उपाय सोचेंगे ही।"

अमरीका में प्रतिबंध: दरअसल, उन्मुक्त व्यापार के सबसे बड़े प्रवक्ता अमरीका के बाजारों में शायद सबसे अधिक प्रतिबंध हैं। अमरीकी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ पावेल के अनुसार, अमरीका ने कारों के आयात पर आठ साल से, ब्राजील के अरंडी के तेल पर १३ साल, जापानी साइकिल स्पीडोमीटर पर १७ साल, कार्बन एवं मिश्रित इस्पात पर २० साल, कपड़ों पर ३२ साल, रबर के जूते-चप्पलों, संतरों, चीनी मिट्टी के टाइल्स और खाना पकाने के बर्तनों पर ५९ साल और कांच के बर्तनों के आयात पर ६६ साल से प्रतिबंध लगा रखा है। कई अन्य चीजों के आयात पर तो १०० साल से भी अधिक समय से प्रतिबंध लगा हुआ है।

और इसके बावजूद अमरीका दूसरे देशों को अपनी नीतियों में उदारता न लाने पर धमकाता है। उसके लिए अमरीकी कंपनियों का मुनाफा बढ़वाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन अमरीका की इस धमकी का एक और पहलू भी है। आज इसी धमकी के कारण उदारता की वकालत करनेवालों की असलियत सामने आ गयी है और इसी उदारता के चलते भारत में अमरीकी पूंजीनिवेश १९८४ के ८.९५ करोड़ रुपए से बढ़कर १९८८ में ९७.१३ करोड़ रुपए हो गया था। १९८४ में अमरीकी कंपनियां भारत से आज की तुलना में काफी कम मुनाफा कमा रही थीं। अगर तब अमरीका ने भारत को धौंस दिखायी होती, तो उसका असर कम होता, लेकिन अगर भारत अपनी उदार आर्थिक नीतियों को जारी रखते हुए अमरीका जैसे देशों पर और आश्रित होता गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तब उसकी आर्थिक आजादी खतरे में पड़ जायेगी।

यह सवाल १९८९ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हीं नेहरू का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिन्होंने भारत को ऐसे दबावों और धमकियों से महफूज रखा था।

—अभय अग्रवाल

पाबंदी की दस्तक: कार्ला हिल्स

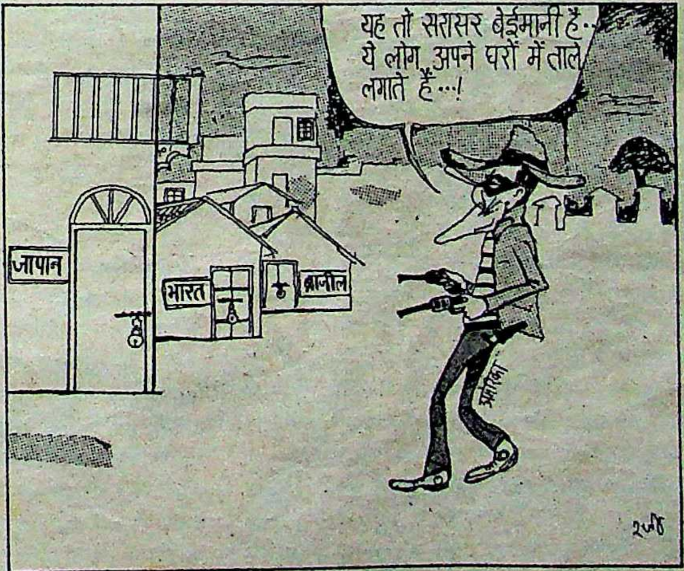
यह तो सरासर बेईमानी है...
ये लोग अपने घरों में ताले लगाते हैं...!
जापान
भारत
ब्राजील
अमरीका

'जनसत्ता' से साभार

बांधवी के बजाय बंधुआ बनाने का रिवाज

आजकल जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि अपने नये प्रधानमंत्री सोसुके ऊनो की पुरानी प्रेमिकाओं को कहां, किस आलमारी में छुपा कर रखे। जैसे ही जापान के साप्ताहिक पत्र 'संडे मैनिची' ने सोसुके ऊनो के भूतपूर्व प्रेमप्रसंगों के बारे में तथ्यात्मक खबर छापी, विदेशी अखबार, पत्र-पत्रिकाएं और टेलीविजन ने इस खबर को पकड़ लिया। सभी ने इस पर एतराज किया कि बगैर अपने अतीत की झाड़पोंछ किये ऊनो प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन हुए। 'संडे मैनिची' ने वर्तमान प्रधानमंत्री की निवर्तमान प्रेमिका से लिये गये एक साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि की कि ऊनो ने चार साल पहले एक स्त्री को २०२७० डालर देकर चार माह तक अपने लिए रक्षित बनाया था। इस स्त्री की उम्र लगभग चालीस साल थी और व्यावसायिक प्रेम के क्षेत्र में आने से पहले वह एक 'गीशा-गर्ल' थी। उस समय सोसुके की उम्र ६२ साल थी। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी तक इस आरोप का खंडन-मंडन, कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "यह मेरा निजी मामला है।"

इस प्रकरण के भंडाफोड़ से कई बातों के संकेत मिलते हैं। एक तो यह कि औरत को अपनी बांधवी के बजाय 'बंधुआ' बनाने का रिवाज प्राचीन और बर्बर माना जाने के बावजूद अभी तक आधुनिक समाज में बरकरार है। इसे अलग-अलग नामों से भले ही पहचाना जाये; चेहरा इसका आज भी वही है, पुरुष द्वारा अपनी सत्ता, संपत्ति और सेक्स की हवस संतुष्ट करने के लिए एक औरत का दुरुपयोग।

मुश्किल यही है। चरित्र और आचरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श करनेवाला कोई मामला किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए मामूली या निजी नहीं कहला सकता। तब तो और भी नहीं, जब वह व्यक्ति देश के सर्वोच्च्च पद पर आसीन हो। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, "प्रधानमंत्री से संबद्ध कोई भी घपला आगे के दिनों पर बहुत खराब असर छोड़ सकता है।" अभी कुछ साल पहले तक जापानी समाज ऐसे घपलों को न तो ज्यादा गंभीरता से लेता था, न इसका खास बुरा मानता था, पर इधर के वर्षों में लोग कुछ ज्यादा ही तुनकमिजाज हो गये हैं। वे नही चाहते कि राजनीतिज्ञों को निजी मामलों के नाम पर आचरण की खुली छूट मिले। जैसे-जैसे विश्व-समाज में स्त्री-पुरुष समानता की चेतना जोर पकड़ रही है, इस तरह के प्रसंगों पर काफी चिंता प्रकट की जा रही है। फिर इस प्रसंग में कहीं भी 'प्रेम' जैसी पावन और उदात्त भावना का उल्लेख नहीं है। किसी स्त्री को सिर्फ पैसों के बल पर अपनी रक्षिता बनाना न सिर्फ स्त्री-पुरुष संबंध का, वरन मानवीय गरिमा का भी अपमान है। चीन और जापान के पुरुष-समाज में 'कानक्यूंबाइन' या 'रक्षिता' रखने के रिवाज पर पर्ल एस बक ने अपने उपन्यासों में काफी मार्मिक विवरण दिये हैं।

जैसे कि इतना सितम काफी न हो, अब तोक्यो की गीशा-मंडल की सदस्य यह ऐलान कर रही हैं कि गीशा चाहे नयी हो या पुरानी, उसे अपना मुह बंद रखना चाहिए, इसी में गीशा समूह कीं प्रतिष्ठा और महत्व निहित हैं। उन्हें उसे भूतपूर्व गीशा से शिकायत है जिसने अखबार को अपना साक्षात्कार दिया। उनके अनुसार, "एक सच्ची गीशा कभी ऐसा नहीं करती। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है जो अखबारवालों से बात करने लगी। इसे पता ही नहीं कि गीशा गर्ल के आचार-व्यवहार के क्या सिद्धांत हैं?"

इस प्रकरण के भंडाफोड़ से कई बातों के संकेत मिलते हैं। एक तो यह कि औरत को अपनी बाधवी के बजाय 'बधुआ' बनाने का रिवाज प्राचीन और बर्बर माना जाने के बावजूद अभी तक आधुनिक समाज में बरकरार है। इसे अलग-अलग नामों से भले ही पहचाना जाये, चेहरा इसका आज भी वही है, पुरुष द्वारा अपनी सत्ता, संपत्ति और सेक्स की हवस संतुष्ट करने के लिए एक औरत का दुरुपयोग। दूसरे, इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में मशगूल व्यक्ति देशसेवा के प्रति उतने समर्पित नहीं हैं, जितना वे दम भरते हैं। उनकी एक अलग रंगीन दुनिया है, जिसमें धन-वैभव के बूते पर खरीदा गया मनोरंजन, दावतों का ठाठ और अंधेरे क्रीड़ा-कक्ष मौजूद हैं।

चुप्पी से बेहतर प्रधानमंत्री ऊनो के लिए यह होता कि वे आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बाब हाक की तरह स्वीकार कर लेते कि उनके जीवन में पत्नी के अलावा अन्य महिला-मित्रों का अस्तित्व था। जनता अपने नेता या हीरो को लेकर एक हद तक दरियादिल हुआ करती है, गलती मान लेने वाले को आधी माफी तो पहले ही मिल जाती है। ग्रीस के प्रधानमंत्री आंद्रे पापेंद्रु को अपने विवाहेतर संबंधों के बारे में कोई कुंठा नहीं है। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के हाथों जब वे और उनकी 'पासोक' पार्टी हार गयी, तब भी उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि इस पराजय में उनके प्रेम प्रसंग की कोई भूमिका हो सकती है। 'प्यार किया तो डरना क्या' के अंदाज में वे दिमित्रा लियानी के साथ अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने गये। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की मृत्यु के कई वर्ष बाद उनके विवाहेतर प्रेम प्रसंगों की चर्चा छिड़ी और इस विषय पर सनसनीखेज पुस्तकों का छपना अभी बंद नहीं हुआ है। इन सारे किस्सों को जो शब्द मर्मस्पर्शिता प्रदान करता है, वह है 'प्रेम'। लेकिन किसी स्त्री को अपनी प्रेमिका बनाने और 'रक्षिता' बनाने में जमीन-आसमान का अंतर है। रक्षिता एक आयामी शब्द है और स्त्री-पुरुष संबंधों को सिर्फ देह की सतह पर देख सकता है। जबकि प्रेमिका बहुआयामी शब्द है और एक ऐसे संपूर्ण संबंध का संकेत देता है, जिसमें पीड़ा और आह्लाद के दोनों छोर सम्मिलित हैं। सोसुके ऊनो के निजी प्रकरण में अब तक एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यही कारण है कि लोग त्योरी चढ़ा कर उस ओर देख रहे हैं।

—ममता कालिया

भला हम क्यों कहें कि हम हैं सबसे बेहतर. हमारे ख़रीदार जो कहते हैं.

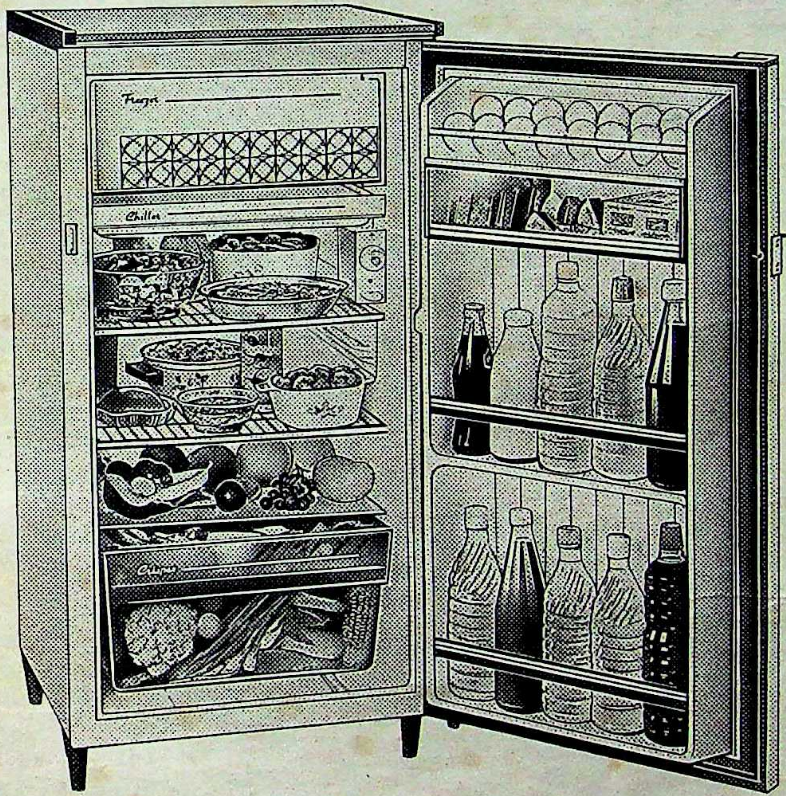

गोदरेज में हमारा हर दिन नयी से नयी तकनीक अपनाने और बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश में ही बीतता है. आज हमारे अत्याधुनिक और पूरी तरह यंत्रचालित कारखाने में आधुनिकतम तकनीक की बदौलत सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के रेफ्रिज़रेटर तैयार होते हैं. ज़रा ग़ौर कीजिए :

- संपूर्ण नया व मज़बूत कम्प्रेसर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 100% पॉलीयूरीथेन इंस्युलेशन. दोनों मिलकर न केवल रेफ़्रिजरेटर के अंदर का तापक्रम कम से कम रखते हैं, बल्कि बिजली की अच्छी-ख़ासी बचत भी करते हैं.
- टिकाऊ व आकर्षक कैबिनेट—ख़ास लुभावने रंगों में.
- ख़ास डिज़ाइन की बदौलत अंदर ज़्यादा चीज़ें रखने की गुंजाइश.

जब लोग गोदरेज रेफ़्रिजरेटर की ही मांग करते हैं तब आश्चर्य क्या कि हम ही हैं देश में सबसे तेज़ी से विकास करनेवाले रेफ़्रिजरेटर निर्माता.

हम सबसे बढ़चढ़ कर हैं, यह हम क्यों कहें. यह तो आप सभी कहते हैं. और यही है महत्त्व की बात.

Godrej® रेफ़्रिजरेटर
सचमुच बेजोड़

HTA 1503

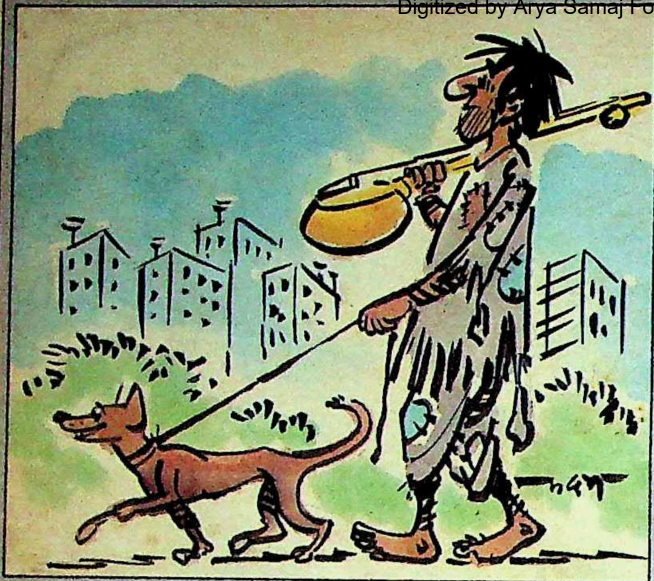

अंधे की लाठी

वह आदमी ही है जो आदमी-आदमी में उसकी हैसियत के हिसाब से फर्क करता है, लेकिन कुत्ते के लिए आदमी सिर्फ आदमी होता है। न वह गरीब होता है, न अमीर। अमीरों का शौक कुत्ते पालना हो सकता है, लेकिन कोई कुत्ता किसी गरीब अंधे की लाठी बन जाये, तो अनुकरणीय तो होगा ही।

मप्र के मांढ़र रेलवे स्टेशन के एक अंधे भिखारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते के बच्चे को उसने चार साल पहले पाला था, वह उसकी आंखें बन जायेगा। उस अंधे भिखारी के जीवन में वह कुत्ते का बच्चा एक देवदूत बनकर आया है। उसकी मदद से वह दूर-दूर तक भीख मांगने जाता है। आगे-आगे वह कुत्ता होता है, पीछे-पीछे रस्सी पकड़े तमूरे पर गीत गाता वह भिखारी। जब कभी वह भिखारी कुत्ते को रेलवे स्टेशन पर छोड़ भीख मांगने ट्रेन से रायपुर से बिलासपुर चला जाता है, तब वह कुत्ता बड़ा विक्षिप्त-सा रहता है। उधर से आनेवाली हर ट्रेन देखता है और प्रतीक्षा करता है। ऐसे कुत्ते को वह बेटे की तरह न माने, तो क्या करे!

संतानदायी कुरसी

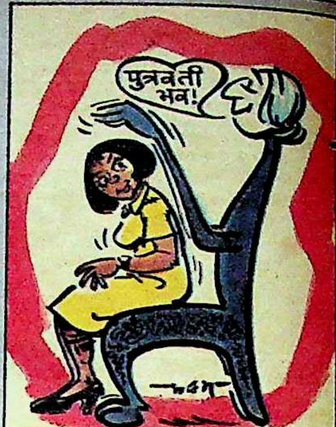

हमारे पुराणों में ऐसी कितनी ही कथाएं मिलती हैं, जिनमें बिना पुरुष के संसर्ग के स्त्री मां बन जाया करती थी, लेकिन वे ऋषियों-मुनियों की बातें थीं। बच्चे के लिए उनका वरदान ही काफी हुआ करता था, न गर्भ धारण करने का झंझट, न आपरेशन, न कोई और तामझाम। लेकिन आज ऐसा होना असंभव है। कोई स्त्री बिना पुरुष के संसर्ग के मां बन ही नहीं सकती। लेकिन कोई स्त्री बिना किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध किये यदि मां बन जाती है, तो घोर आश्चर्य है। लेकिन लंदन में हाल ही ऐसा चमत्कार हुआ है।

दरअसल, ईस्ट लंदन स्थित हाउस एसोसिएशन के दफ्तर में १६वीं शताब्दी से रखी एक ऐसी कुरसी है, जिस पर बैठनेवाली कुंआरी लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और मां बन जाती हैं। कुछ जानकार लोगों का तो कहना है कि इस कुरसी पर किसी प्रेत की छाया है, लेकिन इसमें कितनी सचाई है, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सच अवश्य है कि अब तक बीसों कुंआरी कन्याएं उस पर बैठकर मां बन चुकी हैं। पहले लोगों की ऐसी धारणा बनी थी कि इस कुरसी पर बैठने से कुंआरी लड़कियां ही मां बनती हैं, लेकिन जब एक पचपन वर्षीय महिला भी इस कुरसी पर बैठने से गर्भवती हो गयी, तो वहां की कई बांझ औरतें इस कुरसी पर बैठने के लिए लालायित हो गयीं। लेकिन उस कार्यालय के नियम के अनुसार उस कुरसी पर वही महिला बैठ सकती है जो उस कार्यालय में काम करती हो।

स्वर्णिम चिकन

सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी और लालची बुढ़िया की कथा तो पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहां तो साहब एक मुर्गे के पेट से सचमुच का सोना निकल आया। अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा ही करिश्मा हो गया।

अंग्रेजी अखबार 'इको आफ अरुणाचल' में छपी खबर के अनुसार एक बैंक कर्मचारी एक मुर्गा खरीद कर लाया। जब वह उसे जबह करने के बाद साफ कर रहा था, तो उसकी आंखें फटी-की-फटी रह गयीं। उसने देखा कि मुर्गे के पेट में कोई चीज चमक रही है। खाने की चिंता छोड़ वह बाजार की ओर दौड़ा और पहुंचा एक स्वर्णकार के यहां। जब उसने टुकड़े को स्वर्णकार को दिखाया, तो वह सोने का सात ग्राम का टुकड़ा निकला।

नोटों की झड़ी

एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खुदा जब देता है, तो छप्पर फाड़कर देता है। लेकिन अब वह थैला फाड़ कर भी देने लगा है। फगवाड़ा के बहुतेरे निवासियों की आंखों में उस समय चमक पैदा हो गयी, जब उन्होंने सड़क पर नोटों की वर्षा होते देखी। दरअसल, हुआ यह कि एक स्कूटरसवार स्कूटर भगाने में इतना अलमस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास जो थैला है, उससे नोट सरके जा रहे हैं। स्कूटर सरपट दौड़ रहा था और पीछे नोटों की झड़ी लग रही थी। इस धन-वर्षा को देखकर आबाल-वृद्ध दौड़े और लगे नोट बटोरने। उसी समय चाय के लिए रुके वैष्णव देवी जानेवाले तीर्थयात्री भी नोट देखते ही लपक पड़े। कुछ जिम्मेदार लोगों ने जब यह लूट मची देखी, तो लूटनेवालों को रोका, डांटा-फटकारा और कुछ रुपए भी इकट्ठे करके रखे कि उस स्कूटरवाले को लौटने पर देंगे, लेकिन उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं चला कि उसके नोट कहां-कैसे उसके थैले से छू मंतर हो गये?

संयोजन—डा० मुश्ताक अली

'मुजरिम हाजिर'

सच से साक्षात्कार

'मुजरिम हाजिर में' (बायें से) वीरेंद्र सिंह, राजीव वर्मा और उत्पल दत्त

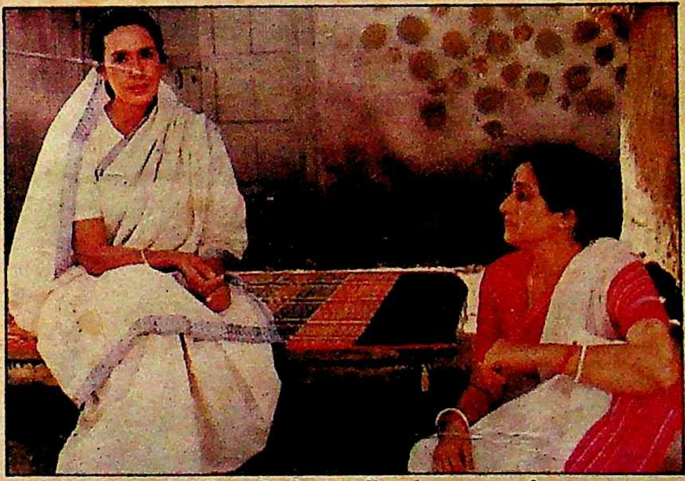

कालीगंज की बहू की भूमिका में नूतन (बायें) और आशा शर्मा

'बनते-बिगड़ते' तथा 'चुनौती' जैसे बहुचर्चित टीवी सीरियलों के निर्माता-निर्देशक राकेश चौधरी का 'मुजरिम हाजिर' पिछले काफी दिनों से चर्चा का इसलिए विषय बना रहा कि जब-जब इसके प्रसारण की योजना बनती या इसकी घोषणा होती, किसी-न-किसी कारणवश प्रसारण खटाई में पड़ जाता। चर्चा के कुछ और भी कारण थे—एक : टीवी सीरियलों से नफरत करनेवाली नूतन ने सीरियलों में काम न करने की अपनी कसम को तोड़कर 'मुजरिम हाजिर' में काम किया था, दो : इसकी गणना महंगे, मल्टी स्टार सीरियल के रूप में की जाती थी, क्योंकि नूतन, उत्पल दत्त, रीता भादुड़ी जैसे फिल्मी सितारे इसमें काम कर रहे थे और निर्माता ने इसके निर्माण में काफी धन व्यय किया था, तीन : 'साहब, बीवी, गुलाम' आदि बहुचर्चित उपन्यासों के लेखक विमल मित्र के प्रख्यात उपन्यास 'आसामी हाजिर' पर यह सीरियल आधारित है।

कहानी : २६ एपीसोडों वाला सीरियल 'मुजरिम हाजिर' नवाबगंज के आततायी जमींदार नरनारायण चौधरी (उत्पल दत्त) द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचारों की कहानी है। एक जमाने में वे कालीगंज के जमींदार हर्षनाथ चक्रवर्ती के यहां पंद्रह रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकर थे। उनके मन में इफरात रुपया कमाने की आकांक्षा थी, इसलिए जब हर्षनाथ और उनके बाद उनके दोनों बेटे चल बसे और परिवार में सिर्फ कालीगंज की बहू (नूतन) रह गयी, तो नरनारायण चौधरी कालीगंज की विशाल जायदाद को नवाबगंज में ठेलकर स्वयं नवाबगंज के जमींदार बन बैठे। कालीगंज की बहू जब नवाबगंज पहुंची, तो नरनारायण को जमींदार के रूप में देखकर सकते में आ गयी। नरनारायण ने उसे टरकाना चाहा। कालीगंज की बहू कोर्ट-कचहरी की बात करने लगी। [illegible] हजार में सौदा पटा, लेकिन वे दस हजार मिलेंगे कब ? दिन-महीने-साल गुजर गये। नरनारायण के बेटे हरनारायण ने जमींदारी संभाल ली।

लेकिन नरनारायण का पोता और हरनारायण का बेटा सदानंद उनके विपरीत ईमानदार तथा सहृदय इंसान है। किसानों का शोषण उससे देखा नहीं जाता। वह बचपन से ही अपने दादाजी का विरोध करने लगता है। सदानंद की उम्र जब पांच-छह साल की रही होगी, तभी से वह देखा करता था कि किस तरह कालीगंज की बहू पालकी में बैठकर आती थी और दादाजी से दुत्कार खाकर लौट जाती थी। वह पालकी के पीछे दौड़ता हुआ चिल्लाता रह जाता, "कालीगंज की बहू...दादाजी झूठ बोल रहे हैं...उनकी संदूक में ढेरों रुपए हैं।

'मुजरिम हाजिर' सदानंद की खुबसूरत पत्नी नयनतारा की भी कहानी है। कुछ लोग सदानंद की धोखे से शादी करा देते हैं। लेकिन सदानद मोहमाया छोड़कर भाग जाता है। ससुर की गंदी हरकतों से परेशान होकर नयनतारा अपने मैके चली जाती है और दूसरे युवक से शादी कर लेती है।

'आसामी हाजिर' भले ही १६७१ से १६७३ के बीच लिखा गया हो, लेकिन इसकी कहानी की पृष्ठभूमि आजादी से पहले, अंग्रेजों के शासन-काल की है। पर इसकी विषयवस्तु आज के संदर्भ में भी एक कटु सचाई है।

'संवाद वीडियो' की प्रस्तुति 'मुजरिम हाजिर' की कहानी में कहानी के पात्रों के साथ-साथ गांव के वातावरण का भी समान दृष्टि से महत्व है। इसका कैनवास भी काफी विस्तृत है। इस सीरियल की कुछ कड़ियों को देखने के बाद महसूस होता है कि राकेश चौधरी ने काफी सतर्कता से काम किया है। उन्होंने जिस ढंग से कलाकारों का चयन किया है, वह काबिलेतारीफ है। उपन्यास के माहौल और परदे पर पेश होनेवाले सीरियल के माहौल में भी समानता नजर आती है। इस तरह काफी हद तक राकेश की बात सच प्रतीत होती है कि 'मुजरिम हाजिर' पर कृति की हत्या का आरोप नहीं लगेगा। उन्होंने इसमें बारीक तथ्यों पर भी विशेष ध्यान दिया है।

सीरियल की कास्ट्यूम डिजाइनर और अपने समय के प्रसिद्ध फिल्म सर्जक विमल राय की पुत्री यशोधरा राय कहती हैं, "इस सीरियल की कास्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए हमने काफी सतर्कता बरती है। इसमें बंगाल की वेशभूषा, रीति-रिवाज पर भी ध्यान दिया है।"

इसके कला निर्देशक समीर चंदा भी मूलतः बंगाली हैं। 'मुजरिम हाजिर' के लिए उन्होंने बाकायदा इतिहास का अध्ययन किया और उस काल को मद्देनजर रखते हुए सेट्स तैयार किये। कलकत्ता के कालीघाट (जहां वेश्यायों का बाजार है) का सेट उन्होंने बंबई में ही लगाया। इसे टीवी पर देखते हुए लगता है जैसे कि हम कलकत्ता पहुंच गये हों।

'मुजरिम हाजिर' में दुष्ट जमींदार नरनारायण चौधरी की भूमिका में उत्पल दत्त, कालीगंज की बहू की भूमिका में नूतन, हरनारायण की भूमिका में राजीव वर्मा, ईमानदार व शोषण के खिलाफ बगावत करनेवाले सदानंद की भूमिका में नये कलाकार वीरेंद्र सिंह ने जान फूंक दी है। सदानंद के बचपन की भूमिका अंतरिक्ष माथुर ने निभायी है। प्रीतिलता की भूमिका में रीता भादुड़ी और प्रकाश मामा की भूमिका में अजीत बच्छानी का अभिनय कहीं-कहीं अटपटा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों सेल्यूलाइड के परदे के बजाय रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों।

—सुषमा त्रिपाठी

शत्रु-काका की दोस्ती

शत्रुघ्न सिन्हा की राजकुमार, अमिताभ बच्चन तथा राजेश खन्ना से कभी नहीं बनी, क्योंकि वे बिहारी बाबू के मुकाबले काफी दबंग आवाज में संवाद बोलकर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। इसीलिए जिन भी फिल्मों में बिहारी बाबू ने इन सितारों के साथ काम किया, वे या तो अधूरी रह गयीं अथवा वर्षों डिब्बे में बंद पड़ी रह कर अपनी सार्थकता खो बैठीं। लेकिन पिछले दिनों बिहारी बाबू राजेश खन्ना से अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर न केवल बोलने के लिए तैयार हो गये, बल्कि उन्हें देखते ही कुछ इस तरह गर्मजोशी से उन्हें अपने आगोश में भर लिया जैसे उनमें कभी मनमुटाव रहा ही न हो। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा कांग्रेस को कोसने की आदत से बाज न आकर राजेश खन्ना के लिए मुसीबत जरूर पैदा कर दी।

'अगर पायलट प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हीरो क्यों नहीं?' बिहारी बाबू की इस उक्ति को सुनकर पहले तो काका नासमझी की मुद्रा में मुस्कराते रहे, लेकिन ज्यों ही शत्रु ने काका की तरफ मुस्करा कर यह फरमाया कि 'आज राजनीति में स्मगलर्स, हाइजैकर्स, डफर्स, ब्रोफर्स और हिस्ट्रीशीटर्स भरे पड़े हैं', काका तमक कर बगलें झांकने लगे। बिहारी बाबू को इस पर भी संतोष नहीं हुआ और काका की तरफ देखकर बोले "आप राजेश खन्ना हैं, राजीव गांधी नहीं, केके तिवारी भी नहीं कि दूरदर्शनवाले आपको कवर करने के लिए यहां तशरीफ लाते।...' बिहारी बाबू ने काका की दुखती रग पर ऐसा हाथ मारा कि काका फीकी मुस्कुराहट के मेकअप में आ गये।

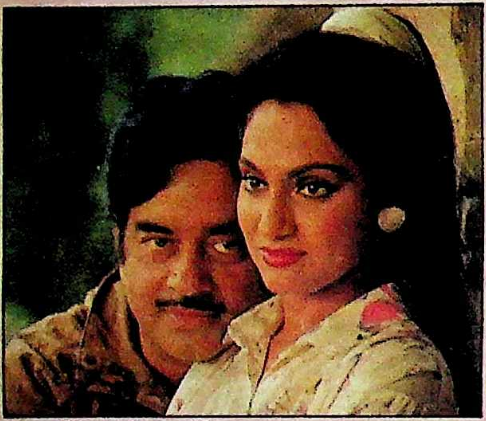

शत्रुघ्न सिन्हा और माधवी

अनुराधा की दहशत

जब से सोलापुर के तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल तथा उनके संगीतकार पति अरुण को सोलापुर ले जाने के लिए खिलौनानुमा पिस्तौल तथा चाकू से धमकाया, तब से अनुराधा-अरुण तो दहशत में हैं ही, दूसरे फिल्मी सितारे भी किसी कार्यक्रम आयोजक का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। सोलापुर (महाराष्ट्र) में २८ जून को आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र देने जब तीन आगंतुक अनुराधा पौडवाल के घर पहुंचे और 'डेट्स' की मजबूरी बतलाकर पौडवाल दंपती ने सोलापुर जाने में अपनी असमर्थता जाहिर की, तो आगंतुकों ने फिल्मवालों से निपटने के लिए फिल्मी स्टाइल अपनाना जरूरी समझा। उन्होंने विशुद्ध अमिताभ बच्चन अंदाज में अपने खिलौना-पिस्तौल तथा छुरे बाहर निकाल लिये और अनुराधा ने भी निखालिस फिल्मी स्टाइल में चीख-चीख कर मजमा जमा लिया। बेचारे आगंतुकों के पास खलनायक अंदाज में भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

अनुराधा पौडवाल

बेटे की मुसीबत

छठे दशक के 'जुबिली कुमार' यानी राजेंद्र कुमार उस समय अपने निर्माताओं के लिए खासे सिरदर्द होते थे और तब उन्हें झेल पाना निर्माताओं तथा सहयोगी कलाकारों के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर होता था। अब वही जुबिली कुमार निर्देशकों के लिए मुसीबतजदा साबित हो रहे हैं। वे अपनी फिल्म के सेट पर निर्देशकों से इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे स्पॉट ब्वाय हों।

राजेंद्र कुमार ने अपने कुमार गौरव को अभिनेता के रूप स्थापित करने के लिए फिल्म 'ल स्टोरी', शुरू की, तो राहुल रवेल 'लव स्टोरी' का डायरेक्टर ब दिया। लेकिन अपने स्वभाव को न बदला। फलतः राहुल ने फिल्म पूरी कर दी, लेकिन अपना नाम दे से मना कर दिया। राजेंद्र कुमार बेटे के लुप्त होते कैरियर को बचा के लिए दो और फिल्में बनायी लेकिन आदत से लाचार होक उन्होंने फिर वही सलूक दुहरा इसका खमियाजा भुगतना प बेचारे बेटे (कुमार गौरव) क फिल्म निर्माता उसे अपनी फिल्मों लेने से घबराने लगे कि क्या पता से पर कब जुबिली कुमार पहुंच क अपने सलूक दुहराने लगें। ऐसे कुमार गौरव को उबारा बीआ चोपड़ा ने, उन्हें 'धर्म शक्ति' में का देकर। तीन दशक पहले बाप को उन्होंने 'धूल का फूल' में काम दे इसी तरह उबारा था। अब बीआ चोपड़ा के सेट पर पहुंच कर कु कहने की जो हिम्मत चाहिए, व बेचारे पिता में कहां?

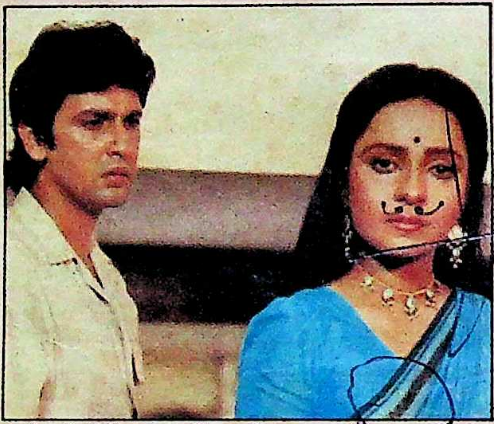

'धर्म शक्ति' में कुमार गौरव और सुजाता मेहता

दीप्ति का नया शौक

एबार्शन तथा बिहारी-पति प्रका झा से दांपत्य संबंधों में तनाव कारण दीप्ति नवल जिन मानसि यातनाओं की शिकार हो गयी लगता है अब उससे काफी हद तक निजात पा चुकी हैं। मानसिक तना के इस दौर में उनका व्यवहार इतन चिड़चिड़ा हो गया था कि बेचा फिल्म निर्माता अपनी अधूरी प फिल्मों को पूरा करने के लिए डेट मांगने तक का साहस नहीं जुटा पा थे। अखबारनवीसों से तो वे इस ह तक खार खाये बैठी थीं कि वे पत्रका भी उनके घर का रुख करने क हिम्मत नहीं करते थे जिनसे क दीप्ति के दोस्ताना संबंध थे।

अंततः इस 'आइस-बर्ग' को निर्माता-निर्देशक बासु भट्टाचार्य ने तोड़ा, दीप्ति के साथ 'पंचवटी' बनाकर तथा रूठे लोगों से दीप्ति की टूटी दोस्ती के तार जोड़कर। इधर दीप्ति को तीर्थयात्रा मेडिटेशन तथा आध्यात्मिकता नया शौक लग गया है। अब देखें नया शौक क्या गुल खिलाता

—अखबारी

'पंचवटी' में दीप्ति नवल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउ
३-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक १६
३१ अगस्त, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना : विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल : सुधीर सक्सेना
जयपुर : ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३३१४७१३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, भोपाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन : ६६३८८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन : २९९०३५ जयपुर कार्यालय : ए-२० शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर-४ फोन : ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

२९

आवरण कथा

विपक्ष ने जिस तेजी से लोकसभा से इस्तीफे देने की रणनीति बनायी और उसे वाम-दक्षिण का भेद भुलाकर लागू किया, उससे लगता है कि विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि चुनाव में राजीव गांधी को परास्त करने के लिए उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के रूप में ब्रह्मास्त्र मिल गया है। बोफोर्स का मुद्दा धीरे-धीरे फीका होता जा रहा था और उसे चुनाव तक जिंदा रखना संभव नहीं था, लेकिन विपक्ष के भाग्य से अब सीएजी रिपोर्ट का छींका टूट गया है। लेकिन क्या विपक्ष इस रिपोर्ट को चुनाव में भुना सकेगा? अचानक टूट पड़े संकट से उबरने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है?

नस्ली वाडिया
बांबे डाइंग के स्वामी नस्ली वाडिया की हत्या के षड्यंत्र का आरोप उद्योगपति अंबानी के उच्चाधिकारी पर क्यों लगा? **६२**

चंद्रशेखर
चंद्रशेखर से समझौता करना क्या इसलिए अनिवार्य है, कि वे जनता दल के लिए अपरिहार्य हैं? **२१**

भाजपा
क्या आगामी चुनाव में भाजपा दिल्ली की सातों सीटें हथियाने में सक्षम है? **८५**

टीवी उद्योग
टीवी के धुआंधार प्रसार के बावजूद क्या टीवी उद्योग पर संकट सन्निकट है? **७२**

बिहार
राजभवन के कर्मचारियों को किस उत्पीड़न का सामना करने के लिए यूनियन बनानी पड़ी है? **५८**

हरियाणा
पिछले दिनों घटित हरियाणा के 'इस्तीफा प्रकरण' की असलियत क्या थी? **५६**

दिल्ली दरबार : दूसरे राउंड का इंतजार १०
विवाद : क्या कांग्रेस अगले चुनाव में भाग ले सकेगी? १७
विचार : क्या हम कूढ़मगज हैं? २४
राडार : प्योंगयांग युवा समारोह : युवा कांग्रेस ने फिर नाम कमाया २७
उत्तर प्रदेश : शक्ति दीक्षा समारोह : अयोध्या में दहशत ४२
उत्तर प्रदेश : श्री गांधी आश्रम : संस्था मालामाल, कर्मचारी खस्ताहाल! ४४
मध्य प्रदेश : गैस पीड़ित : [illegible] ४५
मध्य प्रदेश : पुलिस बर्बरता की नयी मिसाल ४७
मध्य प्रदेश : कृषि वैज्ञानिक डा० आरएच रिछारिया उपेक्षित क्यों हैं? ४९
राजस्थान : विधानसभा में व्यक्ति-स्वातंत्र्य के नमूने ५४
प्रसंगवश : इलाहाबाद-लखनऊ महापालिका चुनाव में हिंसा का खेल ६०
घटनाक्रम : समुद्र के रास्ते आयी तबाही ७०
खोजखबर : एक दिल्ली यह भी! ८८
फिल्म : राज बब्बर कहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें प्रधानमंत्री के आंगन में हैं! ९४

आवरण पारदर्शी
एस पाल ([illegible])

घाटी का सुंदर संसार

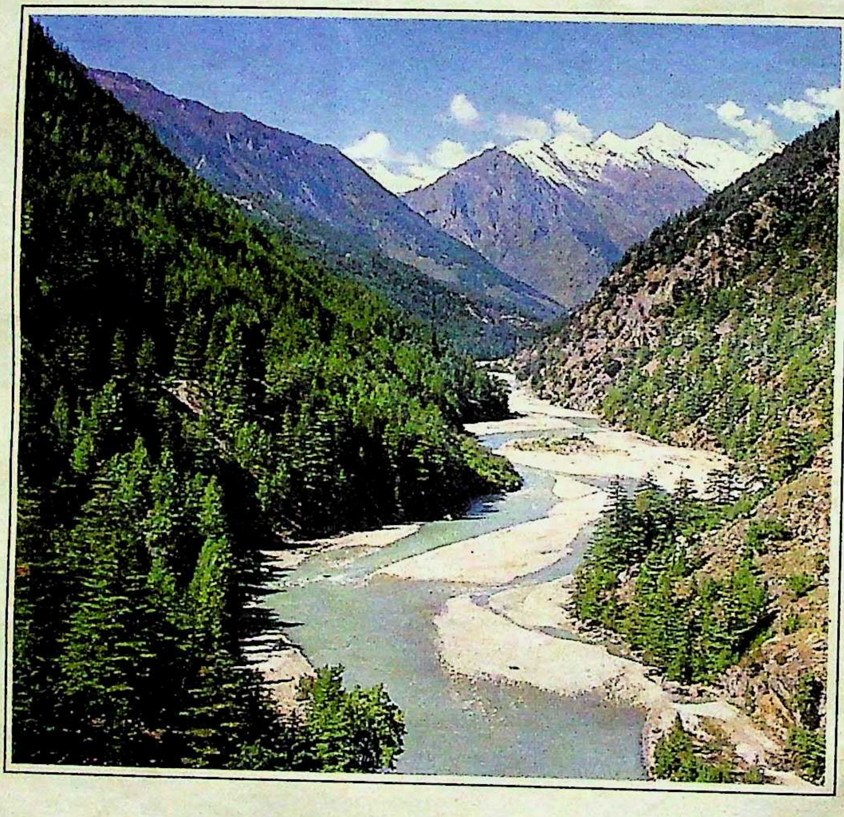

ऊपर. और ऊपर.

पहाड़ों की गोद में खिलखिलाती फूलों भरी घाटियों का सफ़र.

रास्ते में ऊंचे दर्रों का जादुई सौंदर्य.

चारों ओर आसमान भेदते शिखर और पर्वत श्रृंखलाएं जहां प्रकृति का अनंत राज्य है.

लेकिन वादियों की हमारी यात्रा जहां से शुरू हुई, वहां लगा था कूड़े का ढेर.

और फिर पहाड़ तो जैसे कचरे के अंबार बने थे.

यह उन निर्दय सैलानियों का काम था जो हमसे पहले यहां आये.

दुखद बनी राह

डट कर छुट्टी मनाने आये सैलानी जाते-जाते पहाड़ों को सौंप गये अपनी गंदगी के निशान : सड़ता हुआ खाना, ख़ाली डिब्बे, टूटी हुई बोतलें, फटे हुए जूते और झील में सड़ांध फैलाते ढेरों छिलके.

यह धरोहर आपकी है इसे बचाइए

यात्रा सिर्फ़ सैर नहीं, एक खोज भी है.

भारत की अनमोल विरासत : समूची दुनिया में बेजोड़.

पर्यटन विभाग भारत सरकार

पहाड़ पर कूड़े का अंबार

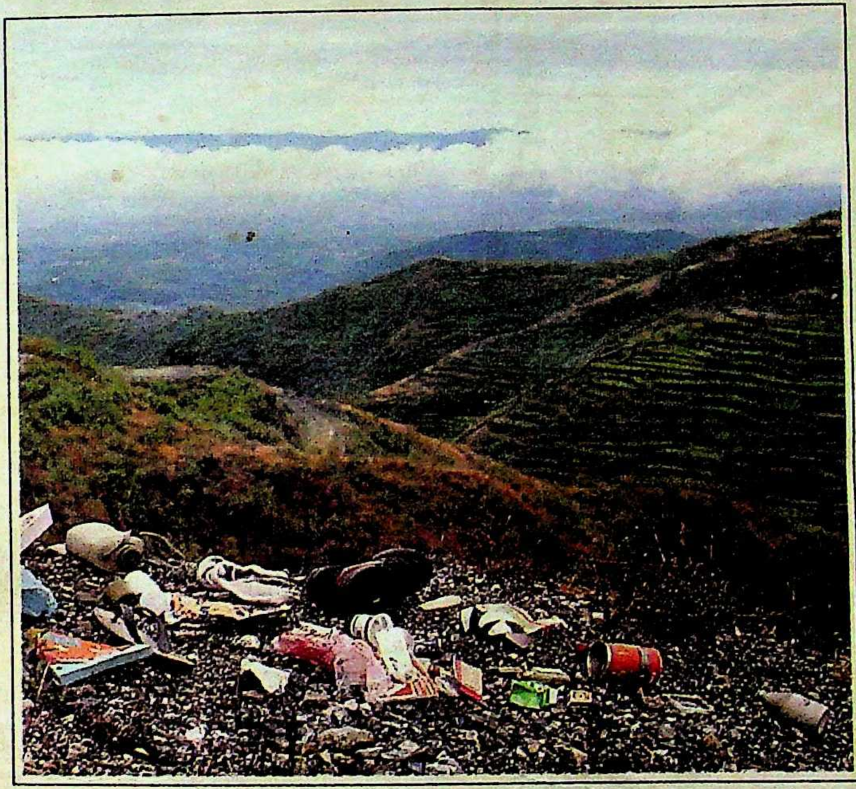

अनगिनत क़िलों, स्मारकों, तीर्थों में गूंजती हुई 5 हज़ार साल की गौरव-गाथा.

और विविधता और वैभव से भरी प्रकृति.

कितने ही रंग और रंगतों में मोहती.

कोई किसी स्मारक को बदशक्ल करता दिखे, किसी पूजास्थल या तीर्थ का अपमान करे या अपने माहौल को बिगाड़ता गंदा करता नज़र आये तो आप चुप न बैठिए.

उसे समझाइए.

उसे रोकिए.

उसकी शिकायत कीजिए.

अपनी अनमोल विरासत को बचाइए.

यही है आपकी धरोहर.

हम ही रचेंगे
हम ही रक्खेंगे

अपना
भारत
सुन्दर

Department of Tourism Government of India

HTA 6241 HIN

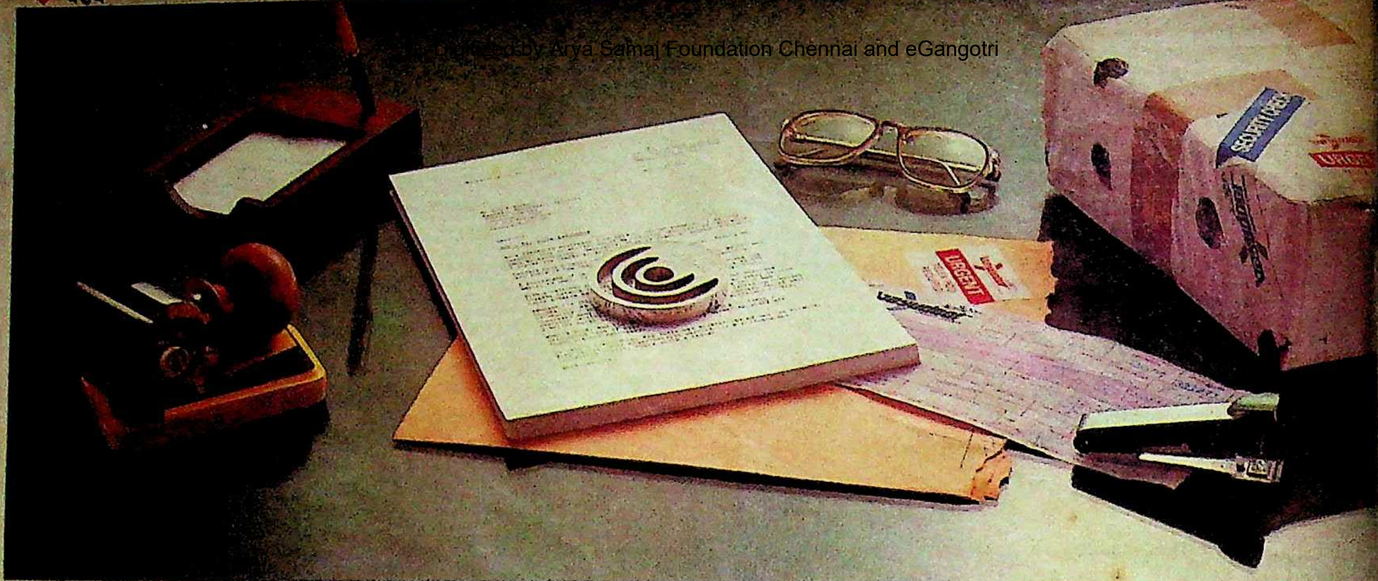

शुक्रिया वायुदूत.
मैंने तो यह सोचा भी न था!

नियमित कुरिअर सर्विस !
क्या बात है !
जब मेरी सेक्रेटरी ने आपका नाम लिया, मुझे तो लगा उसका दिमाग फिर गया है.
बोली, सौ हवाई-स्टेशनों तक आपकी पहुँच है.
और आपके ज़रिए खर्च भी कम पड़ता है.
फिर बोली, आपके पास अपने खुद के विमान हैं.
और इसीलिए उसे आप पर औरों से ज़्यादा गुमान है.
भई वाह ! क्या बात है !
मगर पहले यह तो बताओ कि आपने आखिर मेरी सेक्रेटरी का दिल जीता कैसे?

vayudoot
ULTRA-FAST COURIERS

वायुदूत अल्ट्रा-फास्ट कुरिअरस्. इसके विमान हैं इसकी जान.

अहमदाबाद 467059 बंगलोर 565423, 568513 भोपाल 6285[illegible] 62853 [illegible] 6746583, शिवाजी पार्क 451618 शहर 2048585 कलकत्ता 432727, 434941, चंडीगढ़ 32223, 42643 गुवाहाटी 31676, 31872 हैदराबाद 233411 जयपुर 61269, 62728, 64058-59 कानपुर 208012, 246636 लखनऊ 32104 मद्रास हवाई अड्डा 435160, 435521, शहर 861422, 869901 नई दिल्ली हवाई अड्डा 5481216, 5452126 विस्तारित 2056, नेहरू प्लेस 6466109 सफदरजंग 697716 [illegible]

भाजपा की नीयत

१५ अगस्त, १९८९ की 'माया' ने अपनी आवरण कथा में मौजूदा राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, 'क्या भाजपा अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस को जितायेगी ?' अपनी संदेहास्पद गतिविधि और नीयत के कारण ही भाजपा विपक्षी एकता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। जिस पार्टी की हैसियत अपने गढ़ में ही नगण्य हो, लोकसभा में जिसके मात्र दो सदस्य हों, वह चुनावी तालमेल के लिए राष्ट्रीय मोर्चे से लोकसभा की २०० सीटें मांगे और यह धमकी दे कि इतनी सीटें न मिलने पर वह लोकसभा की ३५०-४०० सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह उसकी भूमिगत मंशा को भी बता जाती है।

वास्तव में भाजपा दोहरी सदस्यतावाले ही लोगों की नहीं, दोहरी चालवाले लोगों की भी पार्टी है। एक तरफ वह हिंदुत्व का नारा देती है, तो दूसरी तरफ अपने सामाजिक-शैक्षणिक कार्यों में हिंदुओं का जबर्दस्त शोषण भी करती है। हिंदू समाज को तो संहार का रास्ता दिखा ही रही है। मैं अभय अग्रवाल की इस टिप्पणी से पूर्णतः सहमत हूं, "भाजपा का उद्देश्य सत्ता में आना नहीं, बल्कि सत्ता का संघीकरण करना है।" आशा है, अन्य राजनीतिक दल और देश के मतदाता भाजपा के दोहरे चरित्र के मायाजाल से स्वयं को और अपने देश को बचायेंगे।

इस अंक में भजनलाल का भांडा फोड़नेवाला लेख और 'विपक्ष का सत्ता संघर्ष' भी बढ़िया रहा। लेकिन फोतेदार की कुछ अधिक तारीफ कर दी गयी है।—**मंजु अस्मिता, हबड़ा, कलकत्ता**

मोतीलाल वोरा : दब्बू या दबंग

३१ जुलाई की 'माया' में 'मोतीलाल वोरा : दब्बू या दबंग ?' पढ़ा। मप्र के मुख्यमंत्री की स्वाभाविक विशेषताओं और कमजोरियों का असरदार खुलासा करने पर सुधीर सक्सेना को हार्दिक बधाई।

मेरे विचार से कोई मुख्यमंत्री दब्बू बनना पसंद नही करता। प्रकृति प्रदत्त संकोची स्वभाव को दब्बूपन नहीं माना जा सकता। इंका के अधिकांश मुख्यमंत्रियों में दब्बूपन परिस्थितिजन्य है। वास्तव में वे अपनी राजनीतिक विवशताओं की वजह से दब्बूपना ओढ़े हुए हैं। अर्जुन सिंह को अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाये, तो इंका के अधिकांश मुख्यमंत्रियों को छोटे अथवा बड़े दब्बू के खिताब से सुशोभित किया जा सकता है। इंका के हर मुख्यमंत्री पर आलाकमान और दिल्ली दरबार की दुधारी तलवार हर समय लटकती रहती है। जाने कब और किस पर गाज गिर जाये, कोई भरोसा नहीं।—**मोहन कुमार कृष्णानी, एच-१८ ओल्ड बैरागढ़, भोपाल, मप्र**

दूरदर्शन का कांग्रेसीकरण

३१ जुलाई, १९८९ की 'माया' की आवरण कथा 'दूरदर्शन का कांग्रेसीकरण' और इसी से जुड़े सूचना-प्रसारण राज्यमंत्री केके तिवारी के साक्षात्कार पर पाठकों की लगभग एक हजार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इन सबको प्रकाशित करना संभव नहीं है। फिर भी पाठकों की भावनाओं का आदर करते हुए हम कतिपय चुने हुए पत्रों के अंश प्रस्तुत कर रहे हैं:

विमल मालाकार ने कटिहार से लिखा है : "'माया' ने निष्पक्षता-निर्भीकता के साथ दूरदर्शन के कांग्रेसीकरण का पर्दाफाश किया है। बेशक सरकारी मीडिया (दूरदर्शन और आकाशवाणी) झूठे, भ्रामक, मनगढ़ंत, अनर्गल बकवासों के प्रसारण का माध्यम बन गयी है। लेकिन देश की जनता यह सब समझ रही है और इस झूठे प्रचार से प्रभावित होनेवाली नहीं।...यह केके तिवारी कौन है ? सूचना-प्रसारण राज्यमंत्री ऐसा सनकी आदमी कैसे हो सकता है जिसके मुंह में इतनी गंदगी भरी है ?" **संतोष कुमार सिंह** झरिया से लिखते हैं : "दूरदर्शन पर दर्शन देना राजीव गांधी का अनिवार्य धर्म हो गया है और झूठ बोलना परम कर्तव्य। दूरदर्शन के इस कदर दुरुपयोग को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।" हजारीबाग के शिवपुरी मुहल्ले के **ओमप्रकाश सिंह** ने अपने पत्र में लिखा है : "सरकारी मीडिया के दुरुपयोग के बारे में जितना भी कहा जाये, कम है। 'दूरदर्शन का कांग्रेसीकरण' (आवरण कथा) और केके तिवारी का इंटरव्यू हूबहू शब्दों में प्रस्तुत कर आपने निर्भीक पत्रकारिता का परिचय दिया है। अगर सम्मानित नेताओं के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल ही राजीव सरकार में मंत्री बनने की कसौटी है, तो सड़क के पागल, केके तिवारी से बेहतर मंत्री हो सकते हैं।" **न्यूयार्क** स्थित फ्रैंकलिन एवेन्यू से **राजकुमार सिंह** ने तो लिखा है, "केके तिवारी का साक्षात्कार पढ़कर दिमागी जायका बिगड़ गया। फूहड़ कथ्य के साथ-ही-साथ जिस छिछली, गलिच्छ और गालीगलौजवाली भाषा का इस्तेमाल तिवारी ने किया है (सुना है वे हमेशा, संसद मे भी ऐसा ही करते हैं), उसका प्रयोग रिक्शेवाला भी नहीं करता होगा। पता नहीं वे पढ़े किस विद्यालय से हैं, पर सुना है पहले कहीं पढ़ाते भी रहे। पता नहीं किसने उन्हें पढ़ाने पर लगाया और कौन इनसे पढ़ता था। खैर राजीव गांधी भी तो आरोपों, तथ्यों, तर्कों का उत्तर न देकर विरोधियों को 'भूंकनेवाले कुत्ते' कहते हैं ! अब जब उन्होंने तिवारी को 'सरकारी प्रचार मदरसे का मास्टर' बनाकर देश पर छोड़ दिया है, तब वे जबरन पढ़ाकर ही छोड़ेंगे। प्रभो, भारत की तुम्हीं रक्षा करो।" सतना के **एसएस सोमवंशी** ने तो केके तिवारी के लिए शर्म-शर्म करते हुए चिंता जतायी है : "भारतीय राजनीति के इतिहास में तिवारी सबसे पहले नेता हैं जिन्होंने वीपी सिंह, हेगड़े जैसे सर्वथा स्वच्छ छविवाले विपक्षी नेताओं के लिए बेहद गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। यह समूची कांग्रेस के लिए शर्म की बात है।" वहीं **एसपी सिंह** उर्फ राजा भइया, जालौन से तिवारीजी को सलाह देते हुए लिखते हैं, "क्या तिवारीजी शिष्ट-संतुलित भाषा में अपने विरोधियों के प्रति विरोध नहीं व्यक्त कर सकते ? काश, हमारे देश में ऐसा कोई कानून होता जिससे ऐसे असभ्य लोगों के बड़बोलेपन पर अंकुश लग सकता।"

◆

आपकी सरकार, आपके द्वार

'माया' का ३१ जुलाई का अंक पढ़ा। 'मोतीलाल वोरा : दब्बू या दबंग ?' विशेष रिपोर्ट मे वोराजी का यह दावा कि 'आपकी सरकार, आपके द्वार' क्रांतिकारी कार्यक्रम है और इसको जबर्दस्त 'रिस्पांस' मिलता है, गलत है। 'आपकी सरकार, आपके द्वार' मात्र दिखावटी कार्यक्रम है। जनता को कोई लाभ नही मिल पाता है। शहडोल जिले के ब्यौहारी, मानपुर, पाली एवं सोहागपुर विकास खंडों में ऐसे शिविर लग चुके हैं। परंतु जनता को कोई अंतिम निर्णय नहीं मिल पाया है। आज भी ग्रामीण जनता राजस्व न्यायालयों के चक्कर काट-काट परेशान हो रही है।
—**कैलाश तिवारी, शहडोल, मप्र**

३१ जुलाई ८९ की 'माया' की 'मोतीलाल वोरा : दब्बू या दबंग' शीर्षक विशेष रिपोर्ट अर्द्धसत्य ही प्रस्तुत करती है। सांसद दिग्विजय सिंह को नस्तर चुभोने में राज्यवर्धन सिंह आंशिक रूप से सफल रहे हैं। यह सही है कि वोरा दब्बू से दबंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु अब माहौल माधवराव सिंधिया के पक्ष में है। यदि इंका को बहुमत मिलने पर सिंधिया को मप्र की बागडोर सौंपी गयी, तो वे अवश्य सफल होंगे।—**महेश त्रिवेदी, नरसिंहगढ़, मप्र**

बड़ा कौन ?

३१ जुलाई, १९८९ की 'माया' में 'बड़ा कौन ?' शीर्षक लेख में सैम पित्रोदा, दूर संचार आयोग के अध्यक्ष तथा संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री गिरधर गोमांगो के आपसी संबंध मधुर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फलतः वैमानिक अन्वेषणों में काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। सैम पित्रोदा जैसे वैज्ञानिक को राजनीतिक तनाव से दूर ही रखना चाहिए ताकि हमारे देश में 'बिजली और पानी' की जटिल समस्या हल हो सके।—**इंद्रचंद प्रसाद, सासाराम, रोहतास**

सात साल बाद

'माया' के ३१ जुलाई के फोटोफीचर में रामाराव को विश्वामित्र के भेष में मंच पर देखा। रामाराव का अचानक सात साल बाद फिल्मों से मोह

◆ चिट्ठियां

का कारण सिर्फ चुनावी-स्वार्थ है। भगवा वस्त्र, त्रिपुंड और तांत्रिक क्रियाओं से जनता की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए ठोस योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता है।**—संजीव सराफ पद्माकरनगर मकरोनिया, सागर**

वीर विक्रम सिंह क्या करें?

३१ जुलाई की 'मायग' में वीर विक्रम सिंह के आपराधिक जीवन की जो विवेचना की गयी है, उससे ऐसा लगता है कि समूचा बुंदेलखण्ड उनसे प्रभावित है। किंतु दूसरा पहलू ऐसा मानने से इनकार करता है, क्योंकि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष में एक असरदार नेता होने के कारण उनकी दखलदाजी है, जिसकी वजह से कुछ नेताओं का अस्तित्व डगमगाता नजर आया। वीर विक्रम सिंह उसी उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा व गुटबाजी का शिकार हुए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें रासुका में बंद किया गया, किंतु पर्याप्त कारण न होने की वजह से उन्हें रिहा भी कर दिया गया। किंतु उप्र के सांगा हत्याकांड में उन्हें अपने आपको निर्दोष साबित करना होगा, उसी आधार पर उनका राजनीतिक जीवन निर्भर होगा।**—चंद्रकुमार ठाकुर, नागौद, सतना, मप्र**

श्रीलंका : शांति सेना से अशांति का खतरा

३१ जुलाई '८९ की 'माया' में समीक्षात्मक निबंध पढ़ने के उपरांत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकरण पर काफी विस्तार से चर्चा की गयी है। यह प्रश्न अब गौण हो गया है कि भारत को 'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले' की स्थिति में खड़ा होना पड रहा है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी अपमानजनक स्थिति में भारत ने अपने को फंसाया ही क्यों?**—रामदास मौर्य, सिविल लाइंस (मीरा भवन के पास) स्टेडियम रोड, प्रतापगढ़, उप्र**

३१ जुलाई '८९ की 'माया' में 'शांति सेना से अशांति का खतरा' लेख पढ़ा। मेरे विचार से भारतीय शांति सेना को राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की धमकी के दबाव में भारत वापस बुला लेना भारतीय विदेश नीति की पराजय मानी जायेगी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका सम्मान के साथ गयी है और उसे सम्मान के साथ लौटना चाहिए। अगर जरूरी हो तो शांति सेना को स्वतंत्र तमिल प्रांत बनाने में भरपूर मदद करनी चाहिए। आखिर भारत ने १,००० सैनिकों की बलि और करोड़ों का धन श्रीलका में सिर्फ, इसलिए नहीं खर्च किया है कि उसे शर्मनाक तरीके से वापस आना पड़े।**—डा० वरुण कुमार, वासुदेवपुर, मुंगेर**

आजाद की पदयात्रा

'माया के ३१ जुलाई, ८९ अक में 'भागवत झा आजाद की रोमांचक पद यात्राएं' पढीं। यह सच है कि आजाद की सहकारिता माफिया पर कार्रवाई के चलते ही इस वर्ष प्रदेश के लोगों को खाद-बीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ा व पैदावार भी अच्छी हुई। आजाद ने खासकर माफिया के घर में घुसकर जिस ढंग से पदयात्राएं की, उससे साफ लगता है कि जनमानस में आजाद की कार्रवाई का तहेदिल से समर्थन था। **—शैलेंद्र सिंह तरकर, सनहौली, खगड़िया, बिहार**

◆ खयालात

यदि श्रीमती गांधी अपनी हत्या के पांच साल बाद स्वयं आकर कह दें कि अमुक व्यक्ति ने मुझे मारा या मरवाया है, तो भी आज के कांग्रेसी नेता हत्यारों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि श्रीमती गांधी को ही पार्टी से निकाल देंगे**—इंका से निष्कासित सांसद एचएन नांजे देवगौड़ा**

रेत में सिर घुसेड़े हुए शुतुरमुर्ग (राजीव गांधी) को सही रास्ते पर आने (लोकसभा भंग करने) के लिए आप कैसे समझा सकते हैं?**—वीपी सिंह, लोकसभा से विपक्ष के इस्तीफे के बाद प्रेस कांफ्रेंस में।**

मैं क्या जानूं कि चांदी के जूते (दलाली के रुपए) किन लोगों ने पायें? मैं तो इतना ही जानता हूं कि मेरे हिस्से लोहे के जूते (निंदा के शब्द) ही आये।**—टीएन चतुर्वेदी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसदों की नाराजगी पर)**

बोफोर्स प्रकरण राजीव गांधी के लिए वाटरगेट कांड सिद्ध होगा।**—भाजपा प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी**

यह डिफेंस (रक्षा) का पैसा है, कोई चारा नहीं कि कोई भी चुग जाये।**—आरिफ मोहम्मद खां**

पिछले पांच सालों के दौरान इतनी दलाली हुई है कि अब हर इंकाई दलाल बन गया है।**—युवा जद अध्यक्ष मोहन प्रकाश**

केके तिवारी

राजीव भइया नहीं चला सकते—यह देश उनके लिए बहुत बड़ा है।**—आनंद भवन (इलाहाबाद) में नेहरू परिवार का एक पुराना सेवक (टाइम्स आफ इंडिया)**

जनता दल एक अजीबोगरीब (रिक्शा) गाड़ी है—ढांचा हरियाणा का, चक्के उत्तर प्रदेश के, हैंडिल हैदराबाद का और इंजन टेलीफोन के तारों से कर्नाटक से बंधा है।**—राजीव गांधी**

राजीव गांधी चोर है।**—लोकसभा में विपक्ष का समवेत नारा**

उनके (राजीव) पास न नाना का व्यक्तित्व है न मम्मी की विरासत, वे सिर्फ कांग्रेसियों की बेवकूफी और बुजदिली की बदौलत बने हुए हैं। **—क्षुब्ध इंका नेता चिमनभाई पटेल**

हमारे लिए अगर कुछ अछूत है, तो सिर्फ कांग्रेस-इ।**—फारवर्ड ब्लाक महासचिव चित्त बसु**

शशि कपूर

वह एक महान दिन होगा, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री-पद पर आसीन होंगे, करीब ५० फीसदी कुटिल (टेढ़े) उद्योगपति रातभर में सीधे हो जायेंगे।**—दत्ता सामंत (इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया)**

राजीव गांधी ने जो प्रणाली चलायी है, उसमें पंचायती राज की मूल अवधारणा ही नदारद है।**—किसान नेता शरद जोशी**

जनता को अधिकार देने की आड़ में अधिकारों के केंद्रीकरण की सरकारी मंशा बेनकाब हो गयी है।**—पब के मुख्यमंत्री ज्योति बसु**

उत्तर प्रदेश सरकार ने नौ सौ शातिर अपराधियों को पेरोल पर छोड़ा है।**—उप्र इंका महासचिव रामकृपाल सिंह**

यह (एनटी गमाराव) उस शख्स का नाम है जो रात में साडी पहनकर औरत की तरह सजता-संवरता है। **—सूचना-प्रसारण राज्यमंत्री केके तिवारी**

केके तिवारी अपने पुश्तैनी गांव (खोरहरा, जिला रोहतास) में न सिर्फ जात-पात का जहर घोल रहे हैं बल्कि हरिजनों को मिलनेवाली जमीन भी खुलेआम लूट रहे हैं। **—सांसद राम अवधेश सिंह**

भारतीय राजनीति में न कोई नायक है न खलनायक, सब-के-सब मूर्ख हैं। **—लेखक-पत्रकार डाम मोरेस, 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया'**

दुर्बल जरासंध का चयन कर बीआर चोपडा ने बिहार का अपमान किया है।**—इंका विधायक जयकुमार पालित**

शादी होने से पहले मेरे पास ४९ प्रस्ताव आये और उनमें से मैंने एक गलत प्रस्ताव चुन लिया, कितनी बुद्धू निकली मैं! **—उपन्यास लेखिका बारबरा कार्टलैंड**

चंद रोज पहले एक करीबी दोस्त की बीवी ने मुझे अपना सच्चा हालेदिल बताया, बोली, "भले तुम मोटे हो जाओ, तुम्हारे बाल सफेद हो जायें, मगर फिर भी तुम मुझे उतने ही प्यारे और अपने शौहर से ज्यादा अच्छे लगोगे।"**—शशि कपूर, 'संडे आब्जर्वर'**

◆

अफसरों ने वीपी को बधाई दी

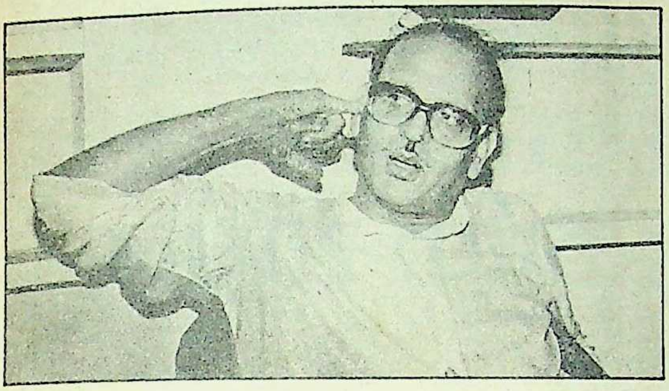

२४ जुलाई को जब १२ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बोफोर्स तोपों पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस्तीफा न देने के विरोध में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो दिल्ली में नौकरशाही का एक वर्ग काफी खुश हुआ। एक सूचना के अनुसार करीब आधे दर्जन सचिव स्तर के अधिकारियों ने जनता दल के अध्यक्ष और भूतपूर्व वित्तमंत्री वीपी सिंह को टेलीफोन करके बधाई दी। लेकिन बाद में कांग्रेसी क्षेत्रों में इस समाचार का खंडन किया गया कि किसी सचिव स्तर के अधिकारी ने वीपी सिंह को कोई बधाई दी है। लेकिन इस सूचना में काफी दम था।

जानकार सूत्रों का कहना है कि वीपी सिंह जब वित्तमंत्री थे, तो उनके सबसे निकट समझे जानेवाले एक बहुचर्चित अधिकारी इस्तीफों से इतने रोमांचित हो उठे कि उन्होंने वीपी सिंह को फोन करके बधाई दी। जब किसी अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या आपने वीपी सिंह को बधाई दी, तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। बताया जाता है कि उक्त अधिकारी के विभाग के मंत्री ने यह जानकारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा दी। लेकिन अधिकारी को इसके बाद भी कोई अफसोस नहीं हुआ।

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अधिकारी से पुछवाया भी कि क्या उन्होंने वीपी सिंह को बधाई दी, तो उनका कहना था कि शिष्टाचार के नाते उन्होंने फोन करके बधाई दी थी। बताया जा रहा है कि अन्य सचिवों के बारे में भी खोजबीन चल रही है कि उन्होंने वीपी सिंह को बधाई दी है या नहीं?

आखिर तिवारी भी बोले!

विश्वनाथप्रताप सिंह के विरुद्ध कांग्रेसी शिविर में मचे कुकुरभूंक में अकेले नारायणदत्त तिवारी ऐसे व्यक्ति थे जो इससे दूर रहे। व्यक्तिगत निंदा-स्तुति से दूर रहना तिवारी का स्वभाव है। पर पिछले दिनों जब वीपी सिंह के बयान के खिलाफ तिवारी ने एक बयान जारी करके कहा कि वित्तमंत्री का काम सिर्फ धन देना नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं और इस बारे में संदेह होने पर वह किसी भी मामले से संबद्ध फाइल मंगा सकता है और उसकी जांच करा सकता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर तिवारी ने अपने स्वभाव के प्रतिकूल आचरण क्यों किया?

राजनीतिक क्षेत्रों की चर्चा के अनुसार जब से बोफोर्स तोप सौदे का मामला उठा है, तब से केंद्र में उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री वीपी सिंह की तीखी आलोचना करते रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने अपना संतुलन कायम रखा। अब यदि तिवारी ने अपना मौन भंग किया है, तो निश्चित ही कहीं-न-कहीं से उन पर दबाव पड़ा है।

तिवारी के बारे में समय-समय पर तरह-तरह की अफवाहें फैलायी जाती रही हैं। यहां तक कि जब ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के मतभेदों को लेकर चर्चा चली थी, तब भी तिवारी को लपेटे में लेने का प्रयास किया गया था। पर उन्होंने तमाम दबावों के बावजूद अपनी शालीनता बनाये रखी और जो नहीं कहना चाहते थे, वह कभी नहीं कहा। लेकिन इस बार वीपी सिंह के बयान की ऐसे व्यक्ति से काट करवानी आवश्यक थी जो भारत सरकार में वित्तमंत्री रह चुका हो, इसलिए उन्हें वीपी सिंह के विरुद्ध बोलना पड़ा। अन्यथा तिवारी विरोधी लाबी उनके खिलाफ और किस्से कहानियां गढ़ती।

लेकिन इस भाषण के बाद तिवारी एक नये सवाल के घेरे में आ गये हैं। तिवारी मंत्रिपरिषद के कई सदस्य अब पूछने लगे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के वित्त राज्यमंत्री ओम प्रकाश रिछारिया इतना साहस बटोर सकते हैं कि जिस खर्च को गलत समझें या जिसके बारे में उन्हें संदेह हो, उससे संबद्ध कागज-पत्र अन्य विभागों से मंगवा लें? रिछारिया यदि इतना साहस बटोरें भी, तो शायद उनके पत्र को वित्त सचिव ही आगे न जाने दे और रिछारिया को यह कह कर चुप करा दिया जाये कि मुख्यमंत्री की इच्छा है। तिवारी भी जानते हैं कि फुफकार के आगे चिराग नहीं जला करते।

जनार्दन ठाकुर के प्रति वीपी की हमदर्दी

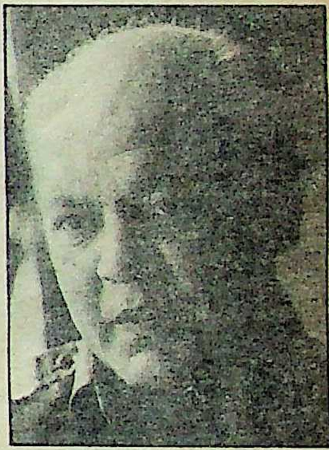

बड़ी उम्मीद थी कि वीपी सिंह को ध्वस्त करनेवाली जनार्दन ठाकुर की किताब 'क्वेस्ट फार पावर' (सत्ता की खोज) खूब बिकेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं कांग्रेस-इ भी किताब की दस हजार प्रतियां खरीदने के वायदे से मुकर गयी है।

आश्चर्य है कि ठाकुर के प्रति जिस व्यक्ति ने हमदर्दी दिखायी है, वह कोई और नहीं, स्वयं वीपी सिंह हैं। वीपी सिंह को दुख है कि ठाकुर का मकसद पूरा नहीं हुआ। वीपी का प्रस्ताव है कि वह पुस्तक की खरीद के लिए एक अपील जारी कर सकते हैं—बशर्ते ठाकुर बिक्री का आधा धन जनता दल के कोष में जमा करने का वायदा करें। जयपाल रेड्डी का कहना है, "हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। धन के मामले में हम कांग्रेस-इ का मुकाबला नहीं कर सकते।" शायद इसीलिए वीपी सिंह जनार्दन ठाकुर से दान की आस लगाये बैठे हैं।

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

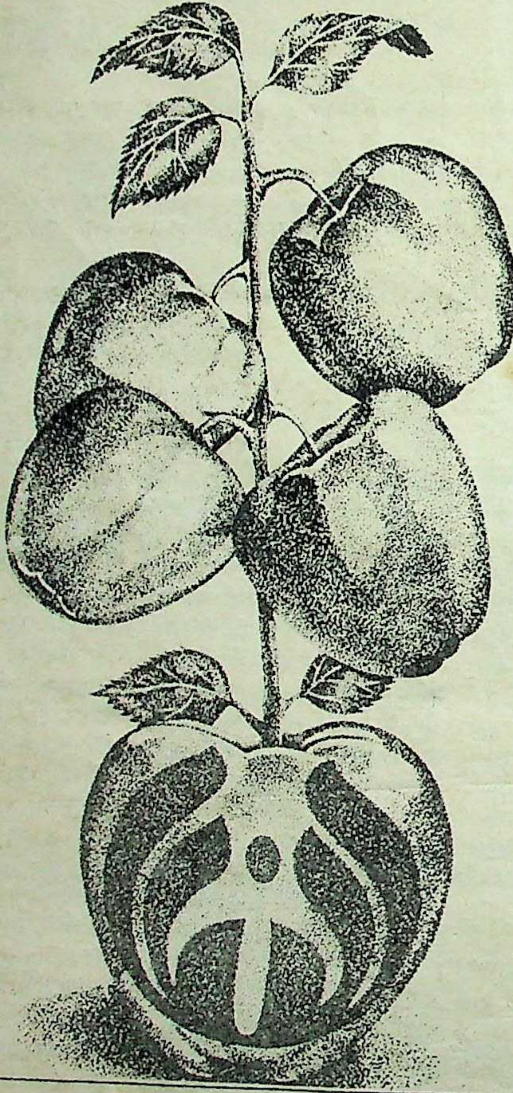

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.वी.आई. टावर, कफ़ परेड, कोलाबा, बम्बई 400005.

Sobhagya-B/89 HN

देश

१६ जुलाई : श्रीनगर में कर्फ्यू लगाकर संदिग्ध घरों की तलाशी, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा २० संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार तथा अवैध हथियार बरामद।

१७ जुलाई : विहार विधानसभा से विपक्ष के नेता लल्लू प्रसाद यादव सहित १० और विधायक पांच दिनों के लिए निलंबित। बाल कल्याण अंतरराष्ट्रीय परिषद की पूर्व अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध लेखिका ७२ वर्षीय तारा अली बेग का निधन।

१८ जुलाई : वित्त राज्यमंत्री अजीत पांजा द्वारा बोफोर्स सौदें पर महालेखा परीक्षक की रपट संसद में पेश, सौदे में खामियों के संकेत।

१९ जुलाई : विपक्ष द्वारा संसद में हंगामा, प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग। क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू हत्या के आरोप से बरी।

२० जुलाई : डा० गोपाल सिंह द्वारा नगालैंड के प्रथम पृथक राज्यपाल की हैसियत से शपथ।

२१ जुलाई : भारतीय युवक कांग्रेस-इ के पूर्व संयुक्त सचिव अतर सिंह टोकस संगठन से निलंबित। ७९ वर्षीय मशहूर सितारवादक मुश्ताक अली खान का निधन।

२२ जुलाई : विपक्षी सांसदों ने संसद से इस्तीफा देने का इरादा किया, वामपंथी और क्षेत्रीय पार्टियों को राजी करने का प्रयास। श्रीनगर के धार्मिक स्थल से हजरत मोहम्मद का स्मृति चिह्न गायब, हिंसा भड़की।

२३ जुलाई : भाजपा द्वारा नौ अगस्त को गद्दी छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का फैसला। १०६ विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा से इस्तीफा देने का निर्णय।

२४ जुलाई : बोफोर्स मामले को लेकर ७३ विपक्षी सदस्यों द्वारा लोकसभा से इस्तीफा, लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ द्वारा इस्तीफे मंजूर।

२५ जुलाई : लोकसभा के निर्दलीय सदस्य काली प्रसाद पांडेय कांग्रेस-इ में शामिल। पाकिस्तान के विदेशमंत्री साहबजादा याकूब खां भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से वार्ता।

२६ जुलाई : महालेखा परीक्षक की बोफोर्स रिपोर्ट पर कांग्रेस-इ द्वारा तीखे प्रहार, कांग्रेस-इ सांसदों द्वारा रामजेठमलानी पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप, लोकसभा से निष्कासन की मांग। लोकसभा में ८९-९० का पंजाब बजट पास।

२७ जुलाई : पूर्व लोकदल विधायक तीरथ सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस-इ में शामिल। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कांशीराम द्वारा बिना किसी दल से तालमेल के चुनाव लड़ने का ऐलान।

२८ जुलाई : हरियाणा के सात मंत्रियों ने अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री देवीलाल को सौंपे। भारत-श्रीलंका में टकराव टला, शांति सेना की वापसी शुरू करने का फैसला।

२९ जुलाई : त्रिकोमाली से भारतीय शांति सैनिकों की वापसी शुरू। अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह रिहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने अपने दामाद को त्यागा।

३० जुलाई : हरियाणा का राजनीतिक संकट टला, मुख्यमंत्री देवीलाल द्वारा छह मंत्रियों के इस्तीफे वापस।

३१ जुलाई : पूर्व कृषिमंत्री राववीरेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा तथा कांग्रेस-इ की सदस्यता से इस्तीफा।

◆

मुश्ताक अली खान

राम जेठमलानी

प्रभाकरन

अदनान खशोगी

विदेश

१६ जुलाई : श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू, तमिल नेताओं के हत्यारों की तलाश जारी। सोवियत संघ में जातीय दंगे, ११ मरे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी पाकिस्तान पहुंचे, प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से वार्ता, संबंध सुधरने के संकेत।

१७ जुलाई : अमरीका गत वर्ष गिराये गये ईरानी यात्री विमान के पीड़ितों को मुआवजा देने को तैयार। अमरीका द्वारा भारत को मिसाइलों के परीक्षण की आधुनिक 'शेक एंड ब्रेक' प्रणाली देने पर पाबंदी।

१८ जुलाई : श्रीलंका के पीपुल्स लिबरेशन आर्गनाइजेशन आफ तमिल ईलम के नेता उमा महेश्वरन की हत्या। बर्मा में मार्शल-ला लागू।

१९ जुलाई : श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांत के मुख्यमंत्री वरदराजन पेरूमल पर हमला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में जातीय दंगे, कर्फ्यू लागू।

२० जुलाई : अमरीकी यूनाइटेड एअरलाइंस का डीसी-१० यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, १९५ व्यक्ति मृत। बर्मा के विपक्ष की नेता श्रीमती आंगसैन सूनकी मिलेटरी शासकों द्वारा नजरबंद।

२१ जुलाई : सलमान रुश्दी के उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' के मसले पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी में फूट। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास ने २९ जुलाई तक शांति सेना की वापसी की जिद छोड़ी।

२२ जुलाई : पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहबजादा याकूब खां श्रीलंका पहुंचे, राष्ट्रपति प्रेमदास से लंबी वार्ता।

२३ जुलाई : श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम के सर्वोच्च नेता वेलुपिल्लै प्रभाकरन की उन्हीं के साथियों द्वारा हत्या। गिपिलिओ आंद्रेओती इटली के नये प्रधानमंत्री बने।

२४ जुलाई : जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के ऊपरी सदन के चुनाव में पराजय, प्रधानमंत्री सोसुके उनो द्वारा इस्तीफे की घोषणा। जान मेजर ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने तथा सर ज्योफरी हाउस आफ कामंस के नेता।

२५ जुलाई : श्रीलंका के त्रिकोमाली जिले में बारूदी सुरंग फटी, २८ भारतीय सैनिक मृत। पोलैंड सालिडेरिटी पार्टी के नेता लेक वालेसा संपूर्ण सालिडेरिटी सरकार के पक्ष में।

२६ जुलाई : हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी को एक करोड़ डालर की जमानत पर रिहा करने का अमरीकी अदालत का आदेश।

२७ जुलाई : दक्षिण कोरिया का यात्री विमान त्रिपोली हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटना का शिकार, ७८ व्यक्ति मृत। स्वीडेन के स्व० प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या के जुर्म में कार्ल गुस्ताव क्रिस्टर पेटरसन को उम्र कैद।

२८ जुलाई : श्रीलंका में भड़की हिंसा को दबाने हेतु कर्फ्यू लागू, कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन, सुरक्षा बलों द्वारा १७५ प्रदर्शनकारी मारे गये।

२९ जुलाई : अली अकबर हाशमी रफसंजानी ईरान के नये राष्ट्रपति बने।

३० जुलाई : ब्रिटेन के नये विदेश मंत्री जान मेजर तथा चीन के विदेश मंत्री छेन छी के बीच हांगकांग मसले पर वार्ता।

३१ जुलाई : पोलैंड में अफगानिस्तान के राजदूत नूर अहमद नूर संयुक्त राष्ट्रसंघ के राजदूत बने।

◆

दूसरे राउंड का इंतजार

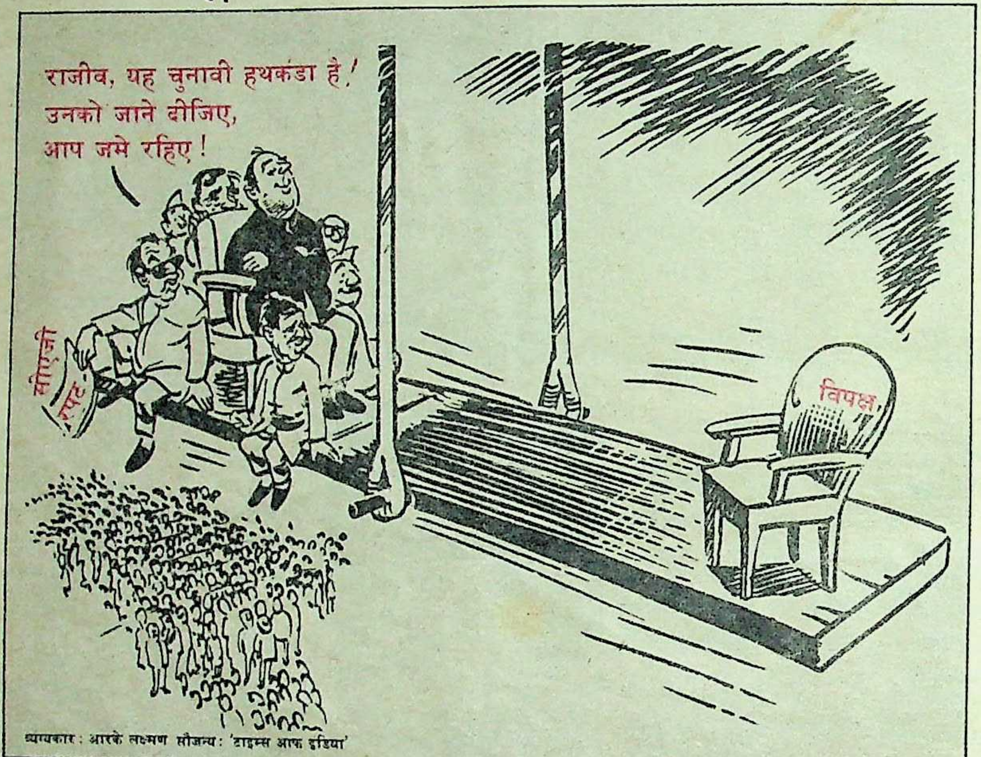
राजीव, यह चुनावी हथकंडा है! उनको जाने दीजिए, आप जमे रहिए!
बोफोर्स
रपट
विपक्ष

व्यंग्यकार : आरके लक्ष्मण सौजन्य : 'टाइम्स आफ इंडिया'

१८ जुलाई यानी संसद के मानसून अधिवेशन के कुछ ही दिनों पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बोफोर्स तोपों के सौदे पर रिपोर्ट दिल्ली दरबार में वाया राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट को कारिंदों ने देखा, तो सकते में आ गये। वे खामोशी से दरबार के कक्ष में गये और बिना किसी टिप्पणी के रिपोर्ट पेश कर दी। दरबार उस समय मुल्क के शहरी इलाकों में लोकतंत्र की जड़ों को खोद कर उसमें मोहसिना किदवई द्वारा तैयार की गयी खाद डाल रहे थे। रिपोर्ट को देखकर दिल्ली दरबार ने कम, लेकिन 'पंचायती राज और जवाहर रोजगार योजना' की वाहवाही कर रहे दरबारियों ने बहुत नाक-भौं सिकोड़ी, "सर, मुर्दा चीजों पर अब आप अपना वक्त जाया न करें। बोफोर्स पूरी तरह दफन हो चुका है। अब मुल्क की पंचायतों में हमारे सरपंच बोफोर्स बीड़ियां पी कर केवल उसका धुआं उगल रहे हैं।" दरबार ने महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पास खड़े अजित पांजा (वित्त राज्यमंत्री) को थमाते हुए इशारा किया कि इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। अजित पांजा ने अपने मुंह से पाइप निकाल कर कहा, "सर, पिछली लोकसभा में हम लोगों ने अपने को पाक-साफ दिखाने के लिए कह दिया था कि आडीटर जनरल की रिपोर्ट जैसे ही हमको मिलेगी, हम उसे सदन में पेश कर देंगे। अब क्या इसे पेश करना है?" दरबार ने कुछ कहने की कोशिश की थी कि उसके पहले ही एचकेएल भगत (संसदीय मंत्री) ने पांजा पर पंजा मार दिया, "इस संबंध में मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी यहां से फूट लो। देख नहीं रहे हो, दरबार शहरी मतदाताओं की जड़ों में खाद-पानी डाल रहे हैं?" अजित पांजा ने अपने मुंह में पाइप फिर से ठूंसा और कक्ष से बाहर निकल आये।

संसद के मानसून अधिवेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा था कि तभी राष्ट्रपति वेंकटरमण की तरफ से उनके सचिव प्रेम कुमार का एक पत्र आ गया, "मुल्क के आडीटर जनरल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जब बोफोर्स तोपों पर अपनी रिपोर्ट देने राष्ट्रपति भवन आये थे, तो उनका अनुरोध था कि यह रिपोर्ट संसद के इसी अधिवेशन में पेश कर दी जाये।" दरबार को जब यह बताया गया, तो उन्होंने हंस कर टाल दिया, लेकिन भगतजी ने तुरंत टिप्पणी कर दी, "वीपी सिंह के भाई की दोस्ती यह पंडित निभाना चाहता है। चुनाव निकल जाये, तो फिर इसको भी देख लूंगा।" भगतजी अपना कटाक्ष खतम ही कर पाये थे कि आरके धवन हांफते-कांपते आ गये, "सर, गजब हो गया। बोफोर्स पर आडीटर जनरल की पूरी रिपोर्ट 'लीक' हो गयी है। अगर उसे संसद में न पेश किया, तो एक तरफ विपक्ष हंगामा करेगा और दूसरी तरफ वह अखबारों में भी छप जायेगी।" भगतजी ने तुरंत कहा, 'धवनजी, एक बार फिर से आईबी के जरिये इसे 'रीचेक' करायें कि क्या सचमुच रिपोर्ट लीक हो गयी है या फिर यह अफवाह फैलायी गयी है? आजकल अपनी आईबी भी बड़ी तेजी के साथ अपनी बचत के लिए अफवाहें फैलाने में लगी है।" धवन ने बताया, "आईबी ने 'रीचेक' करने के बाद ही यह सूचना दी है, लेकिन मैं फिर से इसको 'रीचेक' कराये लेता हूं।"

संसद के मानसून अधिवेशन के प्रथम दिन अजित पांजा ने आडीटर जनरल की बाकी सभी रिपोर्टें पेश कर दीं, लेकिन बोफोर्स से संबंधित रिपोर्ट को अपनी बगल में दबाये घूमते रहे। १८ जुलाई की शाम चार बजे पांजा को संसद स्थित दरबार के कक्ष में बुलाया गया और कहा गया, "चूंकि रिपोर्ट पूरी तरह लीक हो चुकी है, इसलिए इसे भी लोकसभा में पेश कर दो।" पांजा बड़ी खामोशी से लोकसभा गये और उन्होंने सदन में रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद सदन अगले दिन के लिए उठ गया। आदत से

मजबूर जनता दल के प्रोफेसर मधु दंडवते १९ जुलाई की सुबह ही अध्यक्ष के कमरे में उस पर चर्चा की मांग को लेकर चिट्ठी दे आये। प्रोफेसर की समझ में यह नहीं आया कि वे कांग्रेस के जाल में फंस गये। यदि बहस हुई, तो बहुमत की आड़ में कांग्रेस इस रिपोर्ट को लोकसभा के ठंडे बस्ते में दफन कर देगी।

बहरहाल विपक्ष इस जाल में नहीं फंसा और दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा कर दिया और सरकार से इस्तीफे की मांग जोर पकड़ गयी। १९, २० और २१ जुलाई को संसद में जोरदार हंगामा हुआ और सरकार को पसीना आ गया। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने बिलकुल साफ कर दिया कि या तो बोफोर्स तोपों में दलाली खायी गयी है या फिर सरकार मूर्ख है, जिसने इतनी बड़ी दलाली लोगों को खाने दी। दिल्ली दरबार की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निबटा जाये। जिमनास्टिक कर रही शीला दीक्षित ने रुक कर तुरंत सुझाव दिया, "सर, विपक्ष को थका दिया जाये। हम लोग विपक्ष को सदन में रात आठ बजे तक बिठाये रखेंगे।" जब अपनी पीठ खुद ठोंक कर शीला दीक्षित ने सदन को आठ बजे तक बिठाने का प्रस्ताव रखा, तो विपक्ष ने इस नहले पर दहला मार दिया। उसकी तरफ से प्रस्ताव आ गया, "सदन १२ बजे तक बैठे।"

> **जब सीपीआई ने देखा कि बड़ा भाई इस्तीफा देने जा रहा, तो फिर छोटाभाई कैसे पीछे रह जाये? सोमवार, २४ जुलाई को विपक्ष के इस्तीफे हो गये। दिल्ली दरबार ने फिर कोशिश की कि जितने बच गये हैं, उनको इस्तीफा देने से रोक लिया जाये। अंत में हाथी निकल गया, अब दुम पकड़ कर बैठने से क्या फायदा? दिल्ली दरबार हताश होकर बैठ गया। पहले राउंड में विपक्ष ने मैदान जीत लिया।**

२० जुलाई को हैदराबाद में आंध्र के फिल्मी मुख्यमंत्री एनटीआर 'महर्षि विश्वामित्र' की पटकथा को लेकर विचारमग्न थे। वे भावातीत ध्यान में बिना महेश योगी की फीस दिये हुए चले गये। जब वे ध्यान से लौटे, तो उन्होंने पटकथा के पन्ने हवा में उछाल दिये और गुरु गंभीर वाणी में उनके मुंह से निकला, "त्याग...त्याग...त्याग! सब कुछ त्याग दो। उसी में कल्याण है।" महर्षि विश्वामित्र की पूरी यूनिट समझ नहीं पा रही थी कि उनके विश्वामित्र क्या कहना चाह रहे हैं। इतने में एनटीआर ने आकाश की तरफ रहस्यमय ढंग से देखते हुए बोलना शुरू कर दिया, "सबको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद विजयश्री हमारे हाथ लगेगी।" आकाश की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, "फिल्मी यूनिट को भगा दो। अब मैं फिल्मी ड्रामा बाद में, उसके पहले सच्चा ड्रामा खेलूंगा।" एनटीआर के अंगरक्षकों ने विश्वामित्र की पूरी फिल्मी यूनिट को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद एनटीआर ने कहा, "दिल्ली में उपेंद्र को फोन मिलाओ।" एनटीआर के स्टाफ ने तुरंत पी उपेंद्र को टेलीफोन पर हाजिर कर दिया। एनटीआर ने उपेंद्र से पूछा, "वह हमारा राष्ट्रीय मोर्चे का संयोजक कहां है?" उपेंद्र ने जवाब दिया, "वीपी सिंह रांची गया हुआ है।" एनटीआर ने गरज कर कहा, "वीपी को कहो कि अब उसे रांची जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे विश्वामित्र का महामंत्र देना चाहता हूं। विपक्ष के सारे लोकसभा सदस्य त्यागपत्र दे दें।" उपेंद्र ने फोन रखने के बाद सोचा कि कहीं अब एनटीआर को तो रांची नहीं भेजना पड़ेगा?

पी उपेंद्र ने रांची में वीपी सिंह को फोन किया, "एनटीआर ने सुझाव दिया है कि अगर सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है, तो सारे विपक्षी लोकसभा सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए।" वीपी सिंह को उस समय लगा कि अब एनटीआर को भी रांची भेजना पड़ेगा, लेकिन देवीलाल ने वीपी सिंह को डपट दिया, "वह हैदराबादी नचनिया ठीक सोच रहा है। अगर इस्तीफे हो जाते हैं, तो हमको नानी याद दिलानेवालों की नानी याद आ जायेगी।" देवीलाल ने फौरन अपने स्टाफ से कहा, "राजा की कलकत्ता में ज्योति बसु से बात कराओ। मैं अटलबिहारी वाजपेई से बात करता हूं।" वाजपेई से देवीलाल ने बात करने के बाद राजा मांडा की बात भी करा दी। अटलबिहारी वाजपेई ने हामी ही नहीं भरी, दूसरे दिन यानी २२ जुलाई की शाम को सार्वजनिक घोषणा भी कर दी कि अगर और सब त्यागपत्र देंगे, तो भाजपा भी इस्तीफा दे देगी।" ज्योति बसु ने वीपी सिंह से कहा, "मुझे सोचने का मौका दो।" लेकिन दूसरी तरफ से वीपी सिंह ने जोर लगाया, "दादा, अब सोचने का समय नहीं है। यही मौका...।" ज्योति बाबू ने यह कह कर फोन काट दिया, "मुझे अभी-अभी एक पब्लिक मीटिंग के लिए निकलना है, रात को फोन करना।" वीपी सिंह के पीछे लगे खास खुफिया दल ने तुरंत दिल्ली सूचना भेजी कि ज्योति बसु से वीपी सिंह की रात में बात होगी। अभी तक ज्योति बसु ने कोई वचन त्यागपत्र देने के लिए नहीं दिया है।

२२ जुलाई की शाम को जैसे ही यह खबर आयी कि सारा विपक्ष इस्तीफा देने की सोच रहा है, दिल्ली दरबार गहरे सदमे में डूब गये। तुरंत सारे दरबारियों को दरबार में तलब कर लिया गया। राजा दिनेश सिंह को कहा गया कि वे सीपीआई के राजेश्वर राव से संपर्क साधें और उनके लोगों को इस्तीफा देने से रोकें। शीला दीक्षित ने तुरंत कलकत्ता ज्योति बसु को फोन मिलाया। ज्योति बसु ने कहा, "शीला, तुमने बहुत देर कर दी है। वैसे मैंने वीपी सिंह को भी कोई आश्वासन नही दिया है, लेकिन हमारी पार्टी के केरल गुट को ठिकाने लगाने का यह सबसे अच्छा मौका है। फिर भी मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा।" दूसरी ओर अरुण नेहरू के घर 'आपरेशन इस्तीफा दो' का कार्यालय खुल गया। जैसे ही शीला दीक्षित ने ज्योति बसु से बात खतम की, अरुण नेहरू के पास फोन आ गया कि अभी-अभी शीला दीक्षित ने दिल्ली दरबार की तरफ से ज्योति बसु से बात की है। अरुण नेहरू ने फौरन पुश बटन के टेलीफोन पर ज्योति बसु के कलकत्ता नंबर को दबाना शुरू कर दिया, "दादा, अरे शीला दीक्षित से ही बात करते हो। कभी-कभी हमसे भी बात कर लिया करो।" ज्योति बसु ने कहा, "मैं इतवार को दिल्ली पहुंच रहा हूं। ईएमएस से भी बात कर लो।"

इतवार की सुबह तक दिल्ली दरबार को भरोसा था कि सीपीआई और सीपीएम के सांसद इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ईएमएसं की तरफ से इस्तीफे के लिए यह कह कर अड़ंगा लगाया गया कि हम लोग बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं, तो ज्योति बसु ने कहा, "ठीक है। आप न जायें, बंगाल जा रहा है।" ईएमएस यों ही हकलाते बहुत हैं, ज्योति बाबू की धमकी के बाद तो उनकी बोलती ही बंद हो गयी। जब सीपीआई ने देखा कि बड़ा भाई इस्तीफा देने जा रहा है, तो फिर छोटा भाई कैसे पीछे रह जाये?

सोमवार, २४ जुलाई को विपक्ष के इस्तीफे हो गये। दिल्ली दरबार ने फिर कोशिश की, कि जितने बच गये हैं, उनको इस्तीफा देने से रोक लिया जाये। अंत में हाथी निकल गया, अब दुम पकड़ कर बैठने से क्या फायदा? दिल्ली दरबार हताश होकर बैठ गया। पहले राउंड में विपक्ष ने मैदान जीत लिया। दिल्ली दरबार अब कोशिश कर रहा है कि दूसरे राउंड में वह कुछ कर ले।

—दरबारी लाल

अनुसूचित जाति व जनजाति : ७० प्रतिशत गरीब

एक आकलन के अनुसार देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की संख्या कुल आबादी का ४८ प्रतिशत है, लेकिन इन वर्गों के ७० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, अर्थात् उनकी मासिक क्रय-क्षमता सौ रुपए से भी कम है।

मानव अंगों की खरीद-फरोख्त अब अनेक देशों में संगठित व्यवसाय का रूप लेने लगी है और एक गुर्दे की कीमत तीन हजार डालर से २० हजार डालर तक होती है। लेकिन फिलीपीस मे तो १९८७ के पहले तक मौत की सजा पाये उन कैदियो की सजा पर पुर्नविचार होता था जो अपने शरीर का कोई अंग दान कर देता था। १९८७ मे वहां मौत की सजा समाप्त हो जाने के बाद कैदियों ने अपनी सजा कम कराने और अधिकाधिक धन कमाने के लिए अपने अंगों का बाकायदा सौदा करना शुरू कर दिया है।

भारत ने तो परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक करने में रिकार्ड बनाया ही है, लेकिन अमरीका तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। हाल ही न्यूयार्क में हो रही हाई स्कूल की एक परीक्षा में जिस दिन भौतिक शास्त्र की परीक्षा होनी थी, उसके एक दिन पहले शहर के एक अखबार ने न केवल उक्त विषय का प्रश्न-पत्र छापा, बल्कि हर प्रश्न का उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाने के साथ ही सरकार उस अखबार के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

दुनिया के बाजार में अभी तक हथियारों का व्यवसाय पहले नंबर पर था तथा तेल व्यवसाय का स्थान दूसरा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा नियंत्रण फंड के क्षेत्रीय सलाहकार जोर्गन गैमेल गार्ड के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी ने तेल व्यवसाय को पीछे छोड़ कर अब दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। उनके अनुसार हर साल दुनियाभर में तीन खरब डालर मूल्य के नशीले पदार्थों की तस्करी होती है।

नार्वे में हुए एक शोध के अनुसार अनिद्रा के रोगी यदि प्रतिदिन दो-तीन घंटे तेज धूप या तेज रोशनी में रहें, तो उनका यह रोग दूर हो सकता है।

उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में ही लड़कियों ने बाजी नहीं मारी, बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से आयोजित आल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट (हाईस्कूल) की परीक्षा में भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। यहां उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ८४.२ प्रतिशत रहा, तो ८७.६ प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुई। परीक्षा परिणाम ८५.५ प्रतिशत रहा।

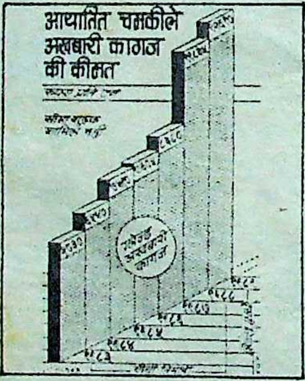

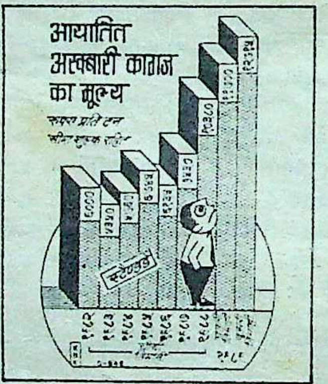

जलगांव जिले के भुसावल कस्बे के सिविल इंजीनियरिंग के छात्र मनोज डी कुजुमदार ने २१ वर्ष की आयु में ही गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कुजुमदार ने टाइपराइटर से श्रीमती इंदिरा गांधी का ४ फुट चौड़ा और १२ फुट लंबा चित्र बनाकर विलक्षण रिकार्ड कायम किया है। कुजुमदार टाइपराइटर से अभी तक महात्मा गांधी, विवेकानंद, मिखाइल गोर्बाचेव, कपिल देव, राजीव गांधी आदि अनेक गणमान्य लोगों के चित्र बना चुके है।

पृथ्वी की मीठे पानी की सोवियत रूस स्थित चौथी सबसें बड़ी झील अराल सागर का अस्तित्व बड़ी तेजी से मिट रहा है। तीस साल पहले इसका क्षेत्रफल ६६ हजार वर्गकिलोमीटर था अर्थात बैल्जियम देश के बराबर, लेकिन अब यह सिकुड़कर ४४ सौ वर्गकिलोमीटर रह गया है तथा इसकी गहराई ९० सेमी प्रतिवर्ष की दर से कम हो रही है। इसका पानी भी मीठा नहीं रहा। आनेवाले कुछ दशकों में अनुमान है कि इस सागर का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और यह पूरा क्षेत्र एक विशाल रेगिस्तान में बदल जायेगा।

ईरान की राजधानी तेहरान ने इस वर्ष दुनिया का सबसे महंगा शहर होने का टोकियो (जापान) का पिछले चार सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनियाभर के १०५ शहरों के सर्वेक्षण में जापान का यह शहर महंगाई की सूची में सबसे ऊपर रहता था, अब यह दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे स्थान पर आनेवाला शहर ओसाका भी जापान में ही है।

आखिरकार, डा० कर्ण सिंह जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरीसिह द्वारा छोड़ी गयी बहुमूल्य संपत्ति के असली मालिक घोषित कर दिये गये हैं। जम्मू-कश्मीर उच्चन्यायालय ने उन्हें तोशखाने में रखे हीरे-जवाहरात के १०३५ जेवरों में से ४२ जेवर कर्ण सिह को सौंपने के आदेश दिये हैं। इन ४२ जेवरों की कीमत ११ लाख रु० आंकी गयी है। शेष ९९३ जेवरात किसे सौंपे जायें, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। विशेषज्ञ समिति ने इनकी कीमत १३९० करोड़ रु० आंकी है। डा० कर्ण सिह को हाल ही अमरीका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने भी हाल ही एक कीर्तिमान बनाया है। केरल विधानसभा ने राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए १९७७ में अस्थायी श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के संबंध में जो विधेयक भेजा था, वह १२ साल बाद इस संस्तुति के साथ लौटा दिया गया कि विधानसभा इसमें समुचित संशोधन करे। केरल विधानसभा अध्यक्ष राधाकृष्णन का कहना है कि यह सामयिक महत्व का एक सामाजिक विधेयक था। इस पर फैसला लेने में इतनी देर होने से इसका महत्व ही समाप्त हो गया है।

आतंकवादी उत्पातों के बावजूद पंजाब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। १९८७-८८ में उसकी विकास दर ७.८ प्रतिशत थी, जबकि विकास का अखिल भारतीय प्रतिशत ९ था। इस वर्ष उसने एक करोड़ ११ लाख टन गेंहू का उत्पादन करके गेंहू उत्पादन में देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है।

विश्व के दूसरे सबसे बड़े और सबसे प्राचीन वट वृक्ष का अंत हो गया है। हाल ही एक भयानक तूफान में यह उखड़ गया। करीब साढ़े चार सौ वर्ष प्राचीन तथा ४० हजार वर्गफुट क्षेत्र में फैला यह वट वृक्ष अदयार (मद्रास) में थियोसोफिकल सोसायटी के प्रांगण में स्थित था। विशेषज्ञ इस वृक्ष को पुन: रोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा वट वृक्ष कलकत्ता में है।

देश में इस समय २२१३ मीट्रिक टन कोयले का अतिरिक्त भंडार है। १९७० के दशक की शुरुआत में आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओआरजी) संस्थान ने "सन—२०२१ में भारत" नाम से एक शोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तब तक भारत की जनसंख्या एक अरब ४० करोड़ हो जायेगी लेकिन भारत की ५ से ९ प्रतिशत की सालाना विकास दर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि तब तक भी देश से गरीबी हटाने का सपना पूरा हो पायेगा। जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय भारत सरकार ने यह संकल्प व्यक्त किया था कि वह बीसवीं सदी के अंत तक देश से गरीबी का अंत कर देगी।

—संयोजन : विनोद मिश्र

राजीव गांधी की विदेश यात्रा

यद्यपि प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी छह दिवसीय (११ जुलाई से १६ जुलाई) विदेश यात्रा के दौरान मुख्य रूप से फ्रांस की राज्यक्रांति के दो सौ साल पूरे होने की स्मृति में आयोजित समारोहों में भाग लेने पेरिस गये थे, लेकिन उनकी यह यात्रा सिर्फ समारोह देखने तक सीमित नहीं थी। पेरिस में एकत्र हुए विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से राजीव गांधी ने मुलाकातें कीं और अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों—खासकर श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के संबंध में भारत के नजरिए से उन्हें अवगत कराया। राजीव गांधी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और कनाडा के प्रधानमंत्री ब्रियान मुलरोनी से अपनी जमीन पर सिख आतंकवादियों को प्रश्रय न देने का आश्वासन प्राप्त किया, तो अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा मितरां ने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के भारत के प्रयासों की प्रशंसा की। तीन दिवसीय पेरिस यात्रा के बाद राजीव गांधी ने मास्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव से भेंट की और लौटते हुए इस्लामाबाद में वे दो दिनों तक रहे। पिछले तीस वर्षों में पाकिस्तान की राजकीय यात्रा करनेवाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनका वहां बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राजीव गांधी पाक राष्ट्रपति इसहाक खां और प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से मिले, प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया तथा उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में भारत की चिंता दो टूक शब्दों में व्यक्त की। भारत लौटने पर राजीव गांधी ने बताया कि इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने तीस राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी श्रीलंका के बारे में कोई बात नहीं पूछी। उक्त चित्रों में बेनजीर भुट्टो द्वारा बैंक्वेट हाल में राजीव गांधी (ऊपर बायें) का स्वागत। राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो (ऊपर दायें), मार्गरेट थैचर (नीचे बायें) तथा फिलीपींस की राष्ट्रपति एक्विनो (नीचे दायें) के साथ।

छाया : पीआईबी

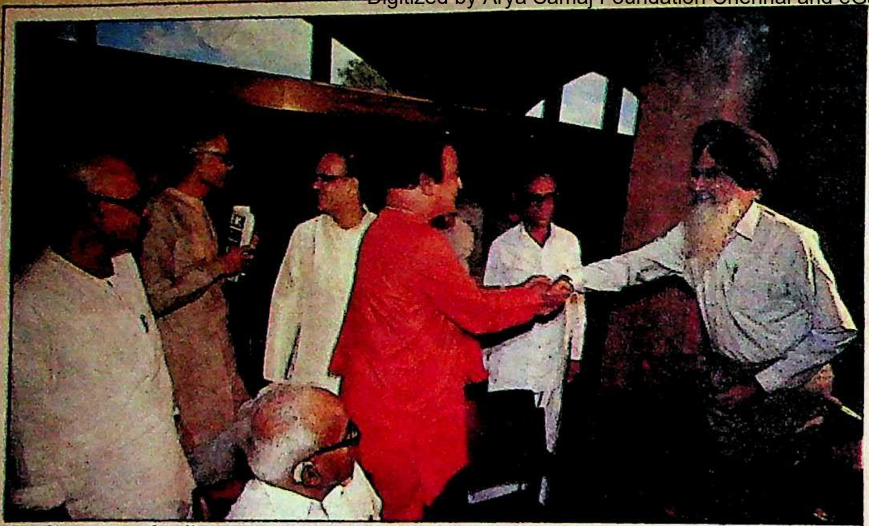

हाथ में हाथ: सुरजीत सिंह बरनाला से हाथ मिलाते एनटीआर तथा नंबूदिरीपाद (कुर्सी पर) व वीपी सिंह

ऐतिहासिक जेहाद

आठवीं लोकसभा के अंतिम मानसून सत्र में राजीव सरकार को झकझोर कर रख देने की विपक्षी नेताओं ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मद्रास के हिंदू दैनिक में किस्तों में प्रकाशित बोफोर्स दलाली के दस्तावेजों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और इस संपूर्ण प्रकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तब तक सरकार ने संसद के पटल पर नहीं रखी थी। लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ से जुड़ा चारा मशीनों का कथित घोटाला और आकाशवाणी व दूरदर्शन के दुरुपयोग सहित ऐसे २६ मुद्दे थे, जिन पर विपक्षी नेताओं ने राजीव सरकार से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया था, लेकिन अगले दिन १९ जुलाई को बोफोर्स तोप सौदों के संबंध में जब भारत के

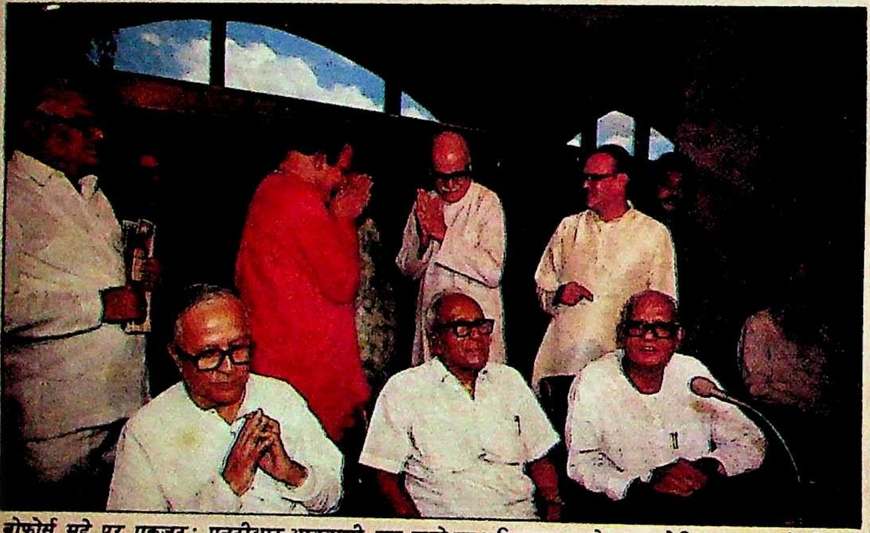

बोफोर्स मुद्दे पर एकजुट: एनटीआर-आडवाणी एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए, ज्योति बसु हाथ जोड़ते हुए

विपक्षी बैठक के समय आंध्र भवन में (बायें से) आरिफ, जयपाल रेड्डी व प्रफुल्ल महंत

छाया : एम पाल

लाल-पीले-नीले झण्डों का मिलन: अटल बिहारी व सुरजीत सिंह बरनाला (हाय मिलाते हुए) ज्योति बसु, नंबूदिरीपाद

आंध्र भवन (दिल्ली) के बाहर विपक्षी-बैठक के समय इंका छात्र संगठन (एनएसयूआई) के एक प्रदर्शनकारी को खदेड़ती पुलिस

छाया : सुनील सक्सेना

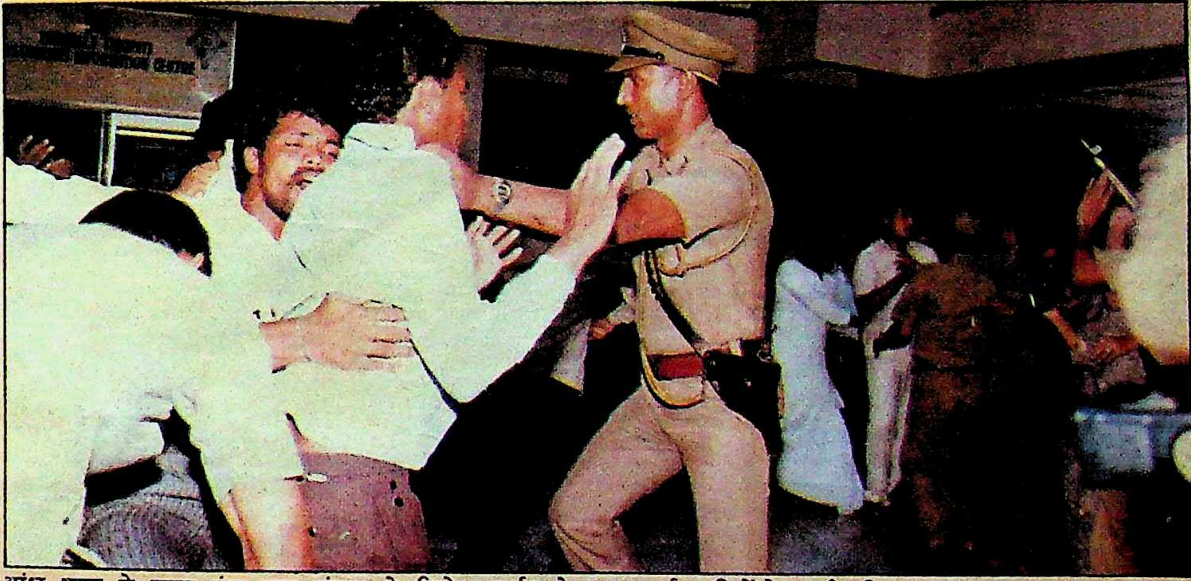

आंध्र भवन के बाहर इंका छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन के समय प्रदर्शनकारियों से जूझती पुलिस

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई, तो धमाका हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का फ्रांस की सोफमा तोपों के मुकाबले न केवल बोफोर्स तोपों का खरीदना अनुचित था, बल्कि सरकार ने खरीदी से पूर्व इसकी गुणवत्ता की आवश्यक जांच पड़ताल भी नहीं की थी। रक्षा सौदों में से भारतीय दलाल तो हटा दिया गया था, लेकिन बोफोर्स से हुए सौदे-समझौते में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि विदेशी कंपनी या किसी विदेशी दलाल को दलाली नहीं दी जायेगी। महालेखा परीक्षक ने इस बात पर भी आपत्ति उठायी कि बोफोर्स तोपों की आपूर्ति धीमी गति से हो रही है, इसलिए इससे भारत की रक्षा तैयारियों में घातक विलंब हो रहा है। सिर पर खड़े आम चुनाव और एकजुट विपक्ष के सपने को साकार करने की कोशिशों में पस्त होते विपक्षी हौसले के बीच महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट ने तात्कालिक स्तर पर ही सही, सभी विपक्षी दलों को वाम और दक्षिण का भेद भुलाकर एकजुट होने का न केवल मौका दिया, बल्कि उन्हें ऐसा मुद्दा भी दे दिया, जिससे वे राजीव सरकार को बचाव की मुद्रा में ला सकते हैं। बहरहाल, बाकी सभी मुद्दे पीछे छूट गये और सारे विपक्षी नेताओं ने राजीव गांधी सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा दिया। राजीव सरकार इस रिपोर्ट पर बहस करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि राजीव गांधी इस्तीफा दें। उसका कहना था कि सरकार द्वारा बार-बार बोफोर्स सौदे में दलाल के अस्तित्व और किसी प्रकार की अनियमितता न बरतने के दावों के बावजूद इन दावों को संदिग्ध साबित करनेवाले दस्तावेज सामने आते रहे हैं और महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट ने तो अब साबित कर दिया है कि राजीव सरकार अपनी प्रामाणिकता खो चुकी है। संसद में जब विपक्षी नेताओं की बात नहीं मानी गयी, तो उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र देकर जनता की अदालत में जाने का ऐतिहासिक फैसला किया। २३ जुलाई को आंध्र भवन में अभूतपूर्व दृश्य था।

१९३९ में अंग्रेजों के शासनकाल में द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत के साधन-स्रोतों को झोंकने के खिलाफ सारे विपक्ष ने इस्तीफा दिया था। पचास साल बाद यह इतिहास फिर दोहराया गया है। उस दिन आंध्र भवन में तेलुगुदेशम, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, माकपा, भाकपा, असम गण परिषद्, अकाली दल, फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी, किसान मजदूर पार्टी व द्रमुक आदि विपरीत ध्रुवोंवाली पार्टियों के सांसदों ने हाथों में हाथ डालकर लोकसभा से त्यागपत्र देने का फैसला लिया। और २४ जुलाई से लोकसभा के विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। लेकिन राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा न देकर सदन में ही रहकर बोफोर्स मुद्दे पर राजीव सरकार का विरोध करने का निश्चय किया।

जिन बोफोर्स तोपों को राजीव सरकार दफन हुआ मामला समझ बैठी थी, वे फिर गरजने लगी हैं। देखना है, विपक्ष इसका कितना चुनावी लाभ ले पाता है।

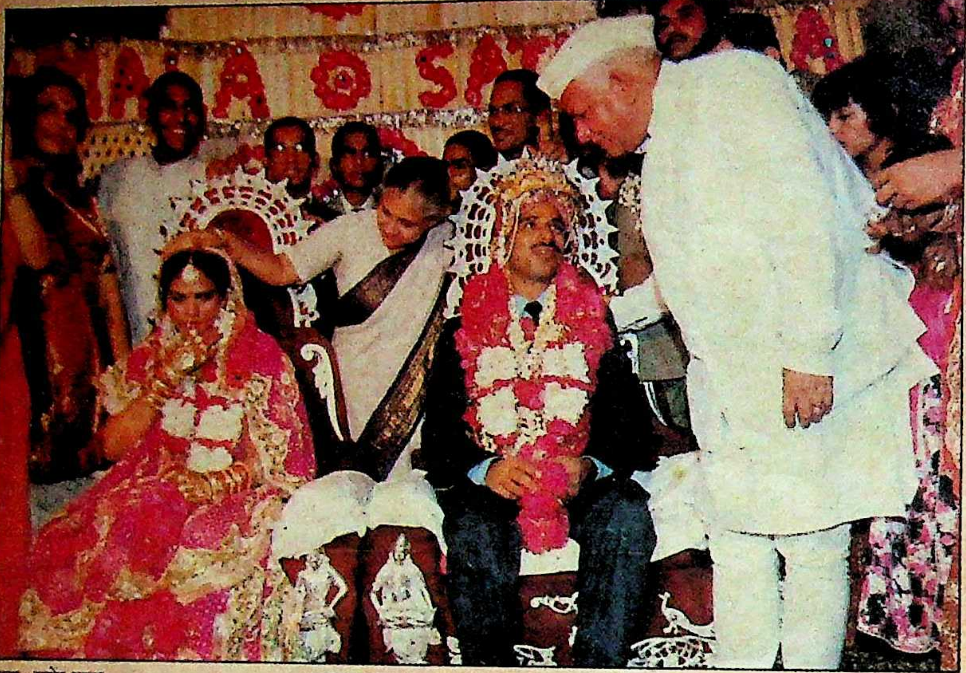

छाया : राजेंद्र कुमार

कमला सिंह का विवाह

केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के आकस्मिक निधन के बाद उनका परिवार खुद को अनाथ न समझे, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने खुद वीर बहादुर सिंह के घर जाकर उनके परिवार को दिया था। और उन्होंने अपना वायदा निभाया। न केवल वीर बहादुर के बड़े पुत्र फतहबहादुर को प्रदेश कांग्रेस का सहसचिव और पुत्री कमला सिंह को राज्य मंत्री का दर्जा देकर महिला कल्याण निगम का अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि १२ जुलाई को भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सत्येंद्र सिंह राणा के साथ कमला सिंह का धूमधाम से विवाह भी संपन्न करवा दिया गया। पिता बनकर नारायण दत्त तिवारी ने कन्या दान किया, तो मां की भूमिका शीला दीक्षित ने निभायी।

चित्र में वर-वधू को आशीर्वाद देते नारायण दत्त तिवारी व शीला दीक्षित।

यासीन मर्चेंट

बंबई के २२ वर्षीय स्नूकर (बिलियर्ड) खिलाड़ी यासीन मर्चेंट ने १५ जुलाई, १९८९ को स्नूकर एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल मैच में थाईलैंड के उदोन खाईमुक को हराकर सबको चौंका दिया।

चौंकानेवाली बात यही नहीं है कि उन्होंने अपने से १४ वर्ष बड़े प्रबल प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया अथवा यह खिताब जीतनेवाले वे पहले भारतीय हैं, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि यासीन मर्चेंट अभी तक राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन भी नहीं हैं, लेकिन उसके पहले वे एशियाई चैंपियन हो गये। बंबई में हुए राष्ट्रीय मुकाबले में वे क्वार्टर फाइनल में तथा गुंटूर में फाइनल मुकाबले में गीत सेठी से हारे, तो गत वर्ष श्रीनगर में हुए फाइनल मुकाबले में श्याम जगतियानी से परास्त हो गये थे। १७ सितंबर, १९६६ को बंबई में जन्मे यासीन मर्चेंट ने ११ वर्ष की आयु से स्नूकर खेलना शुरू किया था। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल के १४ फ्रेमों के कड़े मुकाबले में जिसने भी यासीन मर्चेंट को खेलते देखा है, वह पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि यासीन मर्चेंट स्नूकर में विश्व विजेता का भी खिताब जीतेंगे। १९८५ में यह खिताब गीत सेठी ने जीता था, तो उसके पूर्व माइकेल फरेरा ने इस खेल में भारत का नाम रोशन किया था। अब यासीन मर्चेंट की इस उपलब्धि से उम्मीद करनी चाहिए कि इस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार इसे 'सी' श्रेणी के बजाय 'बी' श्रेणी का खेल मानकर खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

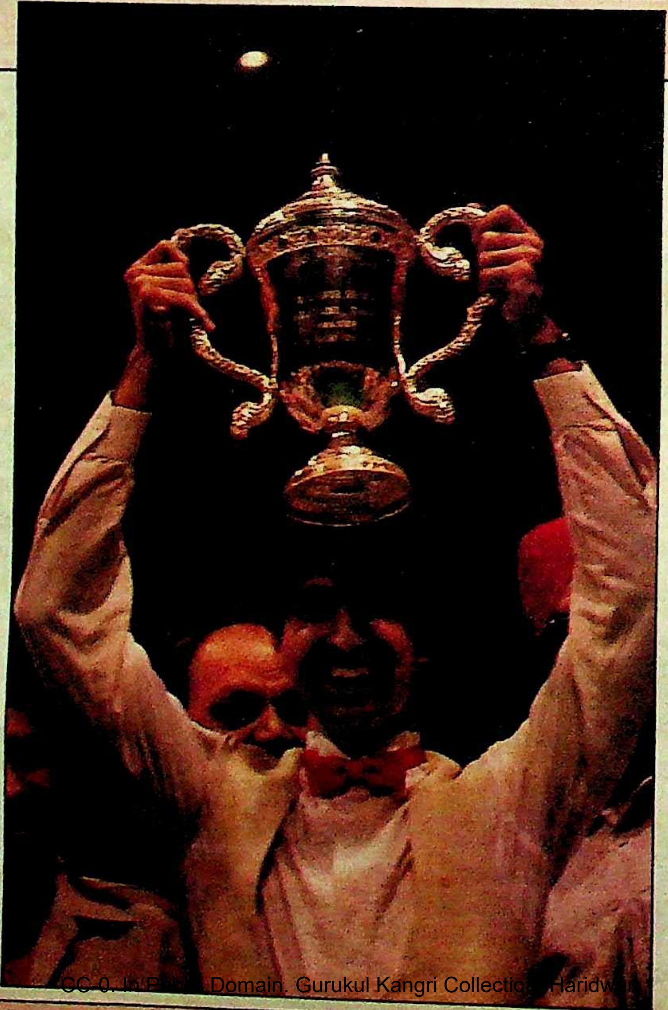

विजित ट्राफी के साथ यासीन मर्चेंट (बायें) :

छाया : सुनील सक्सेना

क्या कांग्रेस चुनाव में भाग ले सकेगी?

पिछले साल अपने प्रचंड बहुमत के बल पर कांग्रेस सरकार ने जो विधेयक पारित कर राजनीतिक दलों को चुनाव से बाहर करने की चाल चली, वह अब सत्तारूढ़ दल के गले की ही फंसरी बन गया है। वह विधेयक क्या है, जिसके कारण कांग्रेस की स्थिति छछूंदर लीले हुए सांप जैसी हो गयी है?

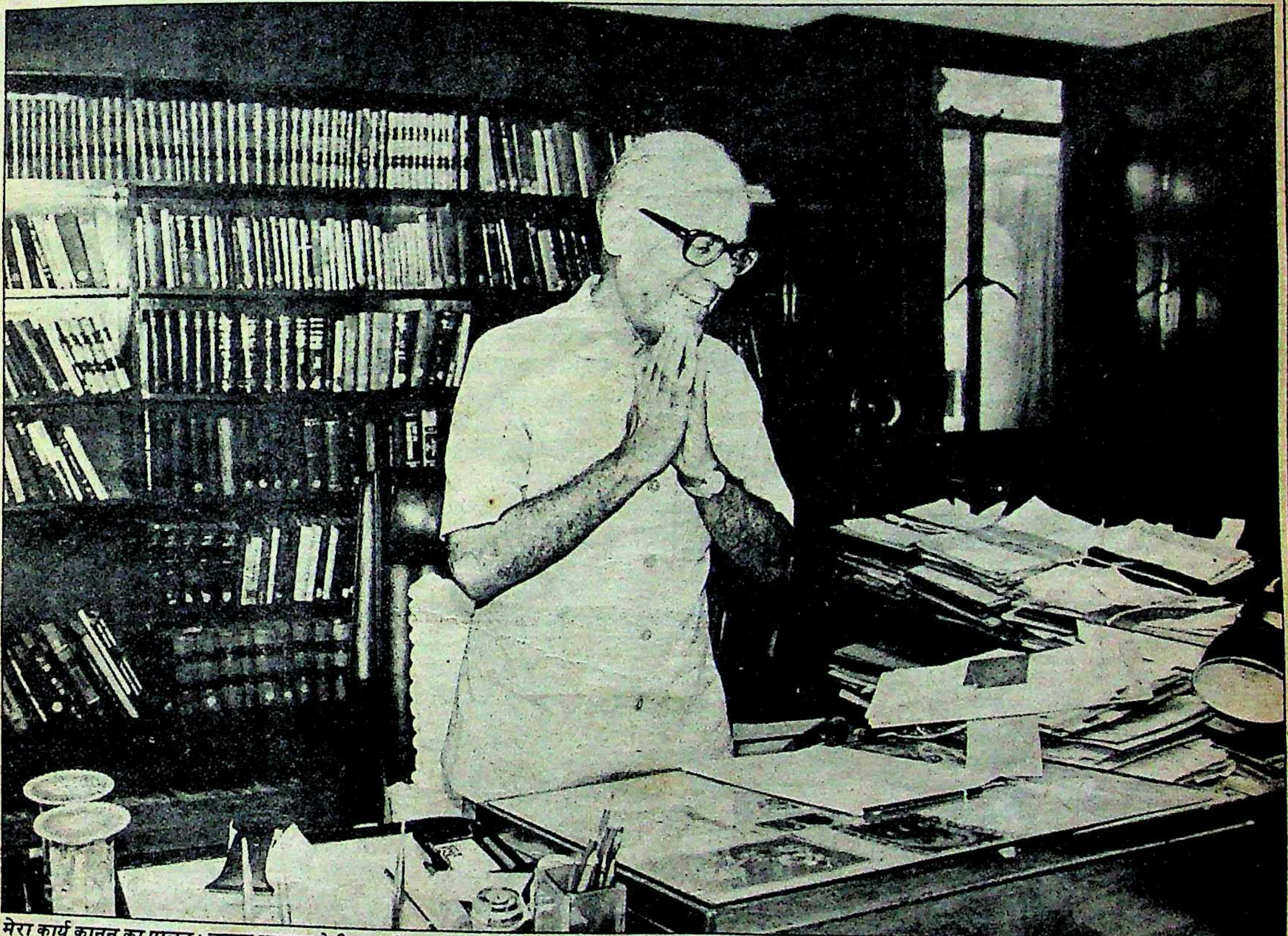

मेरा कार्य कानून का पालन: चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री

छाया: एस पाल

बोफोर्स, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विपक्षी सांसदों के त्यागपत्र की आंधियों के बाद सत्ता की ओर गिद्ध दृष्टि लगाये सत्तापक्ष और विपक्षी दलों की निगाहें अब एक ऐसे शांत बवंडर पर लगी हैं, जो कभी भी फूट पड़ने को तैयार है। बवंडर का केंद्र-बिन्दु है, चुनाव आयोग का शांत मुख्यालय 'चुनाव सदन' और वह इतना शक्तिशाली है कि एक ही प्रहार में आगामी चुनावों के परिणाम ही नहीं, पूरे राजनीतिक पटल को बदल डाले। इस बवंडर का रुख अस्थिर सत्तापक्ष की ओर मोड़ने के लिए भूतपूर्व सांसद और जनता दल नेता कृष्णकांत ने अंधेरे में एक विषवाण छोड़ दिया है जो, यदि निशाने पर लगा, तो कांग्रेस आगामी आम चुनावों में भाग ही नहीं ले सकेगी तथा जनता दल के नेतृत्व में विपक्ष की विजय, चुनाव से पहले ही निश्चित हो जायेगी। यही नहीं, पंजाब में अकाली दल, कश्मीर में जमाते इस्लामी तथा महाराष्ट्र में शिवसेना भी संभवत: चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी।

कांग्रेस की ईसाइयत: कारण गत वर्ष दिसंबर में संसद द्वारा पास किया गया वह विधेयक है जिसके अनुसार चुनाव में भाग लेने के लिए हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में दोबारा पंजीकृत कराना होगा तथा अपने संविधान में परिवर्तन कर स्वयं को 'धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी' घोषित करना होगा। यदि कोई राजनीतिक पार्टी १४ अगस्त तक ऐसा नहीं करती है, तो वह चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी, भले वह

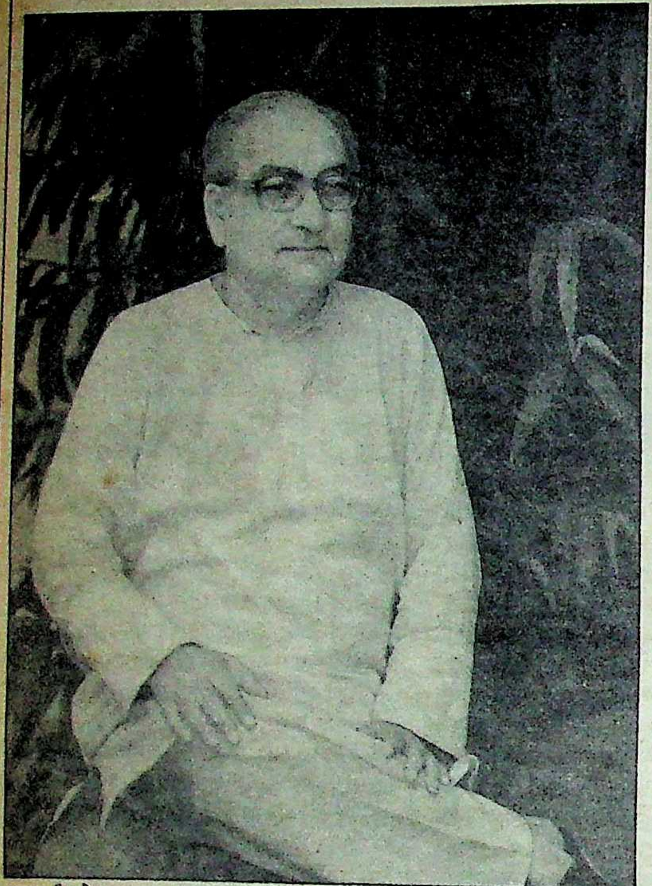

सबूत है घोषणा पत्र : जनता दल नेता कृष्णकांत

छाया : सुनील सक्सेना

प्रश्न उठा, चुनाव आयोग इस प्रकार की भारी गलती किस प्रकार कर सकता है? राजनीतिक पार्टियां किसका आदेश मानें? कानून अथवा चुनाव आयोग का?

सत्तापक्ष कांग्रेस ही क्यों न हो। इंतजार करा रहे बवंडर का सूत्र यह है कि चुनाव आयोग ही यह निर्णय करेगा कि पंजीकृत होना चाहनेवाली पार्टी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी है अथवा नहीं। पर विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि चुनाव आयोग यह निर्णय किस आधार कर करेगा : पार्टी के संविधान पर, चुनाव-घोषणापत्र पर, अथवा पार्टी नेताओं के भाषणों पर। आयोग को डर है कि वह कोई भी निर्णय ले, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा ठोका जायेगा, और सबसे कठिन काम होगा सत्तारूढ़ कांग्रेस के संबंध में निर्णय लेना। जनता दल नेता कृष्णकांत ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख कर कहा है कि विधेयक के अंतर्गत कांग्रेस को पंजीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। पत्र में जनता दल नेता ने हवाला दिया है मिजोरम चुनावों के लिए जनवरी १९८९ में जारी किये गये कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र का। इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने खुलेआम एक ईसाई पार्टी के रूप में अपना प्रचार किया। घोषणा-पत्र में कहा गया, "ईसाई होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करें।" समाजवाद पर कहा गया, "यह आधारित है बाइबल के उपदेशों तथा मिजो संस्कृति पर।" शिक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस घोषणापत्र ने आश्वासन दिया कि स्कूलों का पाठ्यक्रम मिजो संस्कृति तथा ईसाई सिद्धांतों के आधार पर संशोधित किया जायेगा। घोषणापत्र में एक जगह कहा गया कि युक्तियुक्त यही है कि सभी ईसाई कांग्रेस को समर्थन दें।

जनता दल नेता कृष्णकांत के अनुसार, "कांग्रेस का घोषणापत्र स्पष्टत: दिखाता है कि कांग्रेस ने ईसाइयत के नाम पर वोट मांगे। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा १२३ का खुला उल्लंघन है।" जनता दल नेता का मत है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अपनी प्रांतीय या स्थानीय इकाइयों के कार्यों के लिए राष्ट्रीय पार्टी जिम्मेदार है। और चूंकि कांग्रेस ने अभी तक मिजोरम इकाई के घोषणापत्र को सार्वजनिक रूप से नकारा नहीं है, अत: यह कांग्रेस का ही मत माना जायेगा जो कि असंवैधानिक और गैरकानूनी है। चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री से जब 'माया' ने इस प्रश्न पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने कहा, "इस प्रश्न पर मेरी स्थिति न्यायाधीश जैसी है। जब तक दोनों पक्ष अपने बयान मेरे सामने नहीं देते, मेरे लिए कुछ भी कहना अनुचित है।"

कानून की शर्त : पर प्रश्न सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी ६३ राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का है। नए कानून के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए नये सिरे से स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। कानून में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदनपत्र के साथ संगम या निकाय या ज्ञापन या नियम और विनियम की एक प्रति किसी भी नाम से लगी होनी चाहिए। उक्त ज्ञापन और नियमों और विनियमों में एक विशिष्ट उपबंध होना चाहिए कि संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित अनुशासन के अनुसार भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास तथा निष्ठा रखेंगे और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता प्रभुसत्ता और अखंडता बनाए रखेंगे। किसी भी संगम या निकाय को तबतक रजिस्टर्ड नहीं किया जायेगा जबतक कि इसके ज्ञापन या नियमों और विनियमों में उक्त विशिष्ट उपबंध नहीं होता। आयोग यथापूर्वोक्त अपने पास उपलब्ध सभी विशिष्टियों तथा अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात तथा उस संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही उस संगम अथवा निकाय को राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने अथवा न करने का निश्चय करेगा तथा अपना विनिश्चय उस संमग या निकाय को संसूचित करेगा।

कमीशन का कमाल : स्पष्टत: कानून में पार्टी के ज्ञापन या नियम और विनियम की बात की गयी है, संविधान की नहीं। पर गड़बड़ तब हुई जब चुनाव आयोग के शोध अधिकारी केपीजी कुट्टी ने १९ अप्रैल, १९८९ को सभी पार्टियों को एक पत्र लिखा तथा कहा कि हर पार्टी को अपने संविधान में परिवर्तन कर स्वयं को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक घोषित करना होगा। प्रश्न उठा, चुनाव आयोग इस प्रकार की भारी गलती किस प्रकार कर सकता है? राजनीतिक पार्टियां किसका आदेश मानें? कानून अथवा चुनाव आयोग का? लगता है, चुनाव आयोग को अपनी गलती का आभास हो गया पर वह उसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब केपीजी कुट्टी ने १० जुलाई को सभी राजनीतिक पार्टियों को दोबारा पत्र लिखा तो उसमें कानून में कहे गये ज्ञापन अथवा नियमों तथा विनियमों के संशोधन की बात कही, पर फिर भी अपनी गलती नहीं सुधारी और साथ ही 'संविधान' शब्द भी जोड़ दिया। परिणामस्वरूप नये कानून की परिभाषा इतनी पेंचीदा हो गयी है कि हर पार्टी उसका अपना अलग अर्थ निकाल रही है। पर साथ ही डर भी है कि कहीं वह चुनावी अखाड़े से बाहर ही न रह जाये। इस भ्रम का सबसे बुरा असर पड़ा है चार पार्टियों—शिवसेना, अकाली दल, जमाते इस्लामी तथा मुस्लिम लीग—पर।

पार्टियों से जुड़े प्रश्न : शिवसेना की समस्या यह है कि उसके न तो कोई नियम अथवा विनियम हैं और न ही कोई संविधान। ऐसी स्थिति में वह संशोधन किस चीज में करें? शिवसेना में अध्यक्ष बाल ठाकरे के कथन को ही कानून माना जाता है,

तो क्या बाल ठाकरे के एक सार्वजनिक वक्तव्य, कि वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, से चुनाव आयोग का मंतव्य पूरा हो जायेगा ? और यदि लिख कर दे देते हैं तथा बयानबाजी में भारत को हिंदू राज्य बनाने की मांग करते हैं, तो चुनाव आयोग क्या करेगा ? और यदि बाल ठाकरे कहते हैं कि उनका विश्वास हिंदू धर्मनिरपेक्षता में है, तब ? प्रश्न समाजवाद का भी है। समाजवाद पर हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है। यदि बाल ठाकरे कहते हैं कि उनकी निष्ठा हिटलर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय समाजवाद में है, तो किस आधार पर चुनाव आयोग पंजीकरण के संबंध में अपना निर्णय लेगा ? और एक संस्थान के संबंध में जहां बाल ठाकरे का आदेश ही संविधान है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की क्या व्याख्या करेगा ? और यदि शिवसेना को पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो पार्टी के विधायकों का क्या होगा जो महाराष्ट्र विधानसभा में हैं ? क्या उन्हें विधानसभा से निष्कासित किया जायेगा ? और यदि चुनाव आयोग शिवसेना को पंजीकृत कर लेता है, तो बंबई उच्चन्यायालय के उस निर्णय का क्या होगा जिसमें न्यायालय ने शिवसेना को सांप्रदायिक चुनाव प्रचार के लिए दोषी ठहराते हुए विले पार्ले चुनाव क्षेत्र में विजयी शिवसेना उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया था ?

जहां एक ओर हिंदू कट्टरपंथी, मराठा क्षेत्रीयता का झंडा उठाये शिवसेना है वहीं उसकी मुस्लिम प्रतिपक्षी पार्टियां जमाते इस्लामी तथा मुस्लिम लीग हैं। शिवसेना से इनका अंतर मात्र इतना है कि जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग का अपना संविधान है। परिणामस्वरूप जहां शिवसेना दिन-प्रतिदिन अपना रुख बदल सकती है, जमात और लीग के लिए यह संभव नहीं।

शायद यही कारण था कि जमाते इस्लामी ने, जो कि कश्मीर की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी होने का दावा रखती है, जुलाई के आरंभ में अपनी मजलीसे शूरा (कार्यकारिणी) की दो दिन की बैठक बुलायी। बहुतेरे वक्ताओं का मत था कि चुनाव आयोग को झूठा आश्वासन देने के बजाय चुनाव न लड़ना जमात के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि पार्टी का संविधान पवित्र कुरान तथा सुन्नत पर आधारित है, अतः पार्टी द्वारा धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद में विश्वास व्यक्त किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। निश्चित है कि यदि यही रुख पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने लिया, तो वह चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेगी। पर कश्मीर की राजनीति और वहां के जनमानस पर क्या असर पड़ेगा ? क्या जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता और समर्थक यह नहीं कहेंगे कि कश्मीर की एक मात्र पार्टी जो मदरसे तथा पुस्तकालय चलाती है तथा अनेक प्रकार से समाज-सेवा करती है, को दिल्ली सरकार ने चुनाव से बाहर कर दिया है ? क्या इससे पाक-परस्त कश्मीरियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा ? चुनाव आयुक्त से 'माया' ने जब यह पूछा तो उनका कहना था, "यह कानून मैंने नहीं संसद ने बनाया है। मेरा कार्य कानून का पालन मात्र है।"

अकाली दल की समस्या शिवसेना तथा मुस्लिम पार्टियों से भी कठिन है। पंजाब में दो बार सरकार बनाने के बाद अकालियों को बताया जा रहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते। अकाली दल का क्रोध चुनाव आयोग से अधिक गृहमंत्री बूटा सिंह पर है जिन्होंने ३ जुलाई को जालंधर में बयान दिया है कि जबतक अकाली दल संविधान संशोधन नहीं करेगा, उसे चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। बूटा सिंह के बयान की प्रतिक्रिया में अकाली दल महासचिव मंजीत सिंह कलकत्ता ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता की खाल में सांप्रदायिकता फैलानेवाली कांग्रेस अकाली दल को बदनाम कर रही है। यह पूरी सिख कौम तथा उसकी प्रतिनिधि पार्टी शिरोमणि अकाली दल को बदनाम करने की गहरी साजिश है।" अगले दिन ५ जुलाई को अकाली दल के प्रेस सचिव बक्शी जगदेव सिंह ने कहा कि बूटा सिंह के बयान से "अकाली दल को लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में भाग न लेने देने के सुनियोजित षड़यंत्र की बू आती है।" १० जुलाई को संयुक्त अकाली दल के महासचिव ने घोषणा की कि अकाली दल किसी भी प्रकार अपने संविधान में परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि वह धर्म पर आधारित है। यही नहीं, चार दिन बाद अकाली दल (मान गुट) ने नये कानून को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि यह कानून अल्पसंख्यक सिखों की पहचान खत्म करनेवाला अर्थात गैरकानूनी है। साथ ही अकाली गुटों ने निर्णय लिया है कि वे संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र में अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। ऐसे में चुनाव आयोग क्या करेगा ? उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा अथवा अकाली ज्ञापन का इंतजार ? यदि अकाली अपने ज्ञापन में सभी शर्तों को मान लेते हैं, तो भी क्या चुनाव आयोग दल को पंजीकृत कर पायेगा ? क्योंकि दल का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है और न ही दल की सदस्यता गैरसिखों के लिए खुली है। और यदि अकाली दल को पंजीकृत नहीं किया जाता, तो क्या वे राजनीति की मुख्य धारा से अलग-थलग नहीं पड़ जायेंगे ? इसका पंजाब समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रश्न क्रियान्वयन के स्तर पर भी है। यदि कुछ पार्टियां नये कानून के विरोध में न्यायालय जाती हैं तथा चुनाव घोषित कर दिये जाते हैं, तो आयोग क्या करेगा ? यदि आयोग कानून का पालन करते हुए किसी पार्टी का पंजीकरण नहीं करता तथा बाद में कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है, तो क्या आम चुनाव दोबारा होंगे ? जनता दल नेता कृष्णकांत ने 'माया' से कहा है कि यदि कांग्रेस का पंजीकरण किया गया, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे। यदि न्यायालय ने उनकी अपील मान ली, तो क्या कांग्रेस चुनावी अखाड़े से सदा के लिए बाहर हो जायेगी ?

संवैधानिक सवाल : चुनाव आयोग के समक्ष इससे भी अधिक कई जटिल प्रश्न हैं। उन पार्टियों का क्या होगा जो चुनाव आयोग को ज्ञापन में स्वयं को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक घोषित करती हैं पर चुनाव प्रचार अथवा चुनाव बाद आचरण इसके विरुद्ध करती हैं ? क्या चुनाव ऐसे आचरण के आधार पर रद्द किये जा सकते हैं ? राजनीतिक पार्टियों के आचरण की अग्नि-परीक्षा कौन लेगा ? क्या संविधान के अंतर्गत किसी को धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद में विश्वास व्यक्त करने के लिए मजबूर किया जा सकता है ? जब राजनीतिक पार्टियां अपनी आर्थिक नीति भी स्वतंत्र रूप से नहीं बना सकतीं—अर्थात समाजवाद के अलावा दूसरी नीति नहीं अपना सकतीं—तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है ? क्या किसी भी आधार पर चुनाव आयोग एक नागरिक को चुनाव लड़ने से रोक सकता है ? क्या राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण न करना मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता पर आघात नहीं होगा ? क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनाव आयोग लोक तथा गण से सर्वोपरि हो सकता है ? प्रश्न क्रियान्वयन के स्तर पर भी है। यदि कुछ पार्टियां नये कानून के विरोध में न्यायालय जाती हैं तथा चुनाव घोषित कर दिये जाते हैं, तो आयोग क्या करेगा ? यदि आयोग कानून का पालन करते हुए किसी पार्टी का पंजीकरण नहीं करता तथा बाद में कानून को न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है, तो क्या आम चुनाव दोबारा होंगे ? जनता दल नेता कृष्णकांत ने 'माया' से कहा है कि यदि कांग्रेस का पंजीकरण किया गया, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे। यदि न्यायालय ने उनकी अपील मान ली, तो क्या कांग्रेस चुनावी अखाड़े से सदा के लिए बाहर हो जायेगी ?

इस प्रकार कांग्रेस सरकार अपने ही कानून में फंस गयी है। निश्चित ही प्रश्न बहुत जटिल है पर चुनाव आयोग शांत है। बवंडर बन रहा है और राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उसी पर लगी हैं। आगामी चुनावों में क्या होता है, यह बहुत हद तक इस पर आधारित होगा कि इस बवंडर में कौन बच पाता है ?

—अभय अग्रवाल

जनता दल

चंद्रशेखर की अहमियत

यद्यपि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद विपक्षी राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। आपसी कलह की दस्तकें धीमी हो गयी हैं और एकता का स्वर मुखर हो गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से जनता दल में चंद्रशेखर और वीपी सिंह को लेकर जो उठापटक चल रही थी, क्या उसका पटाक्षेप हो गया? क्या जनता दल के लिए चंद्रशेखर अपरिहार्य हैं?

समझौता वार्ताओं के लंबे 'शांतिपाठों' के बावजूद विपक्षी एकता पर दुराशंकाओं की काली छाया कायम है। सात सदस्यीय समिति की वेदी पर 'चंद्रशेखर हटाओ' अभियान की बलि चढ़ाने के बाद जनता दल के शीर्ष नेता एक बार फिर आपस में हाथ मिलाते हुए मुस्कराये। जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले राजधानी में तेजी से घटे तनावपूर्ण घटनाक्रमों ने अचानक जैसे पूरी विपक्षी राजनीति का परिदृश्य ही बदल दिया। राजनीतिक महाभारत की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के हिस्से में आयी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल के बीच तीन घंटे लंबे सहभोज की खुशबू और 'सात सदस्यीय समिति' के जन्म की बधाइयां।

समझौते की सजा: 'चंद्रशेखर जनता दल से निकाल दिये जायेंगे,' 'चंद्रशेखर जनता दल तोड़ कर खुद ही बाहर हो जायेंगे,' 'चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप सिंह को खतम करने के लिए कांग्रेस से मिल गये हैं।' पूरे एक महीने से राजधानी में घुमड़ रहीं ये दुराशंकाएं थम पायी थीं कि जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव यशवंत सिन्हा ने अचानक इस्तीफा देकर एक बार फिर धमाका कर दिया। सिन्हा चंद्रशेखर के खास सिपहसालार माने जाते हैं। ऐसी हालत में १४ जून को हरियाणा भवन में हरियाणा के बुजुर्ग जाट नेता की मध्यस्थता में हुए 'दो ठाकुरों' के बहुचर्चित समझौते के ठीक एक पखवाड़े के अंदर ही सिन्हा के इस्तीफे को जहां एक वर्ग युद्धविराम का उल्लंघन मान रहा है, वहीं दूसरा तबका इसे 'समझौता' न लागू करने की 'सजा' की संज्ञा दे रहा है। इसके बावजूद जनता दल में यह माननेवालों की कमी नहीं है कि शीर्ष नेताओं के आपसी झगड़ों को दूर करने के लिए होनेवाला हर समझौता फार्मूला अपने साथ अगले विवादों के भ्रूण लेकर आता है। दिल्ली प्रदेश जनता दल का मामला सात सदस्यीय समिति को न सौंप कर महासचिव अजीत सिंह द्वारा सीधे वीपी सिंह से पास करा लेने की यशवंत सिंहा की शिकायत भी इस शृंखला की सिर्फ एक कड़ी मात्र है।

यह सिर्फ संयोग नहीं है कि 'समझौते' को एक मल्ल-दांव के रूप में इस्तेमाल करने और फिर समझौते की शर्तों की दुहाई देकर अगली चाल चलने के इस 'इस्तीफा शैली युद्ध' के दोनों महारथी विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जनता दल में आमने-सामने अड़े हुए हैं। हर बार दोनों तरफ से उठनेवाली तलवारें समझौतों की म्यान में जाकर और ज्यादा जहरीली होती गयी हैं। पर ११ अक्तूबर '८८ को बंगलौर में जनता दल की स्थापना के बाद से ही अलग-थलग पड़े चंद्रशेखर को खुलकर तलवार निकालने का मौका पूरे छह महीने बाद १६ मई '८६ को मिला, जब जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिहार प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रघुनाथ झा को हटाने का ऐलान किया। रघुनाथ झा को हटाने का आदेश जारी भी खासे रहस्यमय ढग से हुआ। उस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह दिन भर जनता दल के मुख्यालय में बैठे थे और उन्होंने जनता दल सचिवालय की बैठक में भाग लिया था। बैठक में कई फैसले भी लिये गये। पर सिंह ने झा की बाबत कोई चर्चा तक नहीं की। रात को सिंह को ट्रेन से उत्तर प्रदेश जाना था। दिल्ली छोड़ने से कुछ देर पहले सिंह ने अपने घर से झा को हटाने की चिट्ठी हाथ से लिखी और उसकी प्रति 'इंडियन एक्सप्रेस' दफ्तर भेज दी। वहां से यह खबर बाकी जगह पहुंचायी गयी।

नया समीकरण: पर अजीत सिंह से लेकर बाकी अपने तमाम साथियों द्वारा छोड़े जाने के बाद लंबे अरसे से अलग-थलग पड़े चंद्रशेखर कुछ महीने पहले ही एक गुपचुप राजनीतिक दांव चल चुके थे। कभी चंद्रशेखर को गलियां देनेवाले शरद यादव से उनकी गुपचुप मुलाकातों का क्रम चल पड़ा था। वहीं देवीलाल के बड़े बेटे और हरियाणा जनता दल अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से चंद्रशेखर की बैठकों का दौर भी तेज हो गया था। इन दोनों की मार्फत चंद्रशेखर ने देवीलाल तक यह संदेश पहुंचवाया कि यदि उन्हें 'राजा' और 'चौधरी साहब' के बीच में से किसी एक को चुनना हो, तो वे चौधरी साहब को चुनेंगे, क्योंकि 'चौधरी साहब' बुजुर्ग हैं, उन्होंने

चंद्रशेखर को निकालने की तिकड़म: वीपी सिंह

इस मोर्चे पर तैनात लोगों का मानना था कि १४ जून की सुबह-सुबह लेख जब देश भर में पढ़ा जा रहा होगा, ठीक उसी समय जनता दल के संसदीय बोर्ड में चंद्रशेखर को दल से निकालने की कार्रवाई पूरी हो रही होगी।

जिंदगी भर संघर्ष किया है तथा वे जमीन से जुड़े रहे हैं आदि-आदि। देवीलाल कैंप तक जब यह खबर पहुंची, तो अनेक भक्तों ने भी जोर मारा, "चौधरी साहब अगला प्रधानमंत्री तो आपको ही बनना चाहिए। सारे लोग तो आपके साथ हैं।" निश्चित तौर पर विपक्ष का यह बुजुर्ग जाट महारथी दरबारियों की इस हवाबाजी में आसमान में उड़ने लग जाये, यह तो संभव नहीं था। पर इस समझौते के दो नतीजे साफ निकल कर सामने आये। एक, उसके फौरन बाद हुई जनता दल की बैठक में चंद्रशेखर-देवीलाल जोड़ी का विश्वनाथ प्रताप सिंह से झगडा, जिसमें नाराज सिंह की इस्तीफा देने की धमकी पर देवीलाल ने कहा, "जा-जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे राजा" और विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठक से उठ कर बाहर चले गये थे। इसके बाद राजधानी में देर रात तक विपक्षी नेताओं की भागदौड़ और वार्ताओं की कसरत के बाद कहीं जाकर देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह का समझौता हो पाया था। जनता दल के ही एक वरिष्ठ नेता इस संबंध में अपनी व्याख्या पेश करते हुए कहते हैं, "शायद देवीलाल भी जानते थे कि फिलहाल उन्हें इतनी ही दूर तक जाना है। बैठक के उस पूरे नाटक का मकसद सिर्फ 'राजा' को यह बताना भर था कि वे उनका कंधा छोड़कर ऊपर न उड़ें और इस तरह आक्रोश दिखाकर वे अपनी ताकत भी तौलना चाहते थे। उस दिन दोनों ही मकसद पूरे हो गये।"

देवीलाल की चाल : चंद्रशेखर-देवीलाल के बीच हुए संवादों का दूसरा नतीजा था, उत्तर भारत में जनता दल की प्रदेश इकाइयों को पूरी तरह राजा की मुट्ठी में जाने से बचाना। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जहां मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ल, हिमाचल में रामलाल और बंगाल में अशोक सेन को अध्यक्ष बनाया, वहीं देवीलाल-चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान आपस में बांट लिये। चंद्रशेखर को इस पर संतोष करना पड़ा कि बिहार में उनके रघुनाथ झा और उत्तर प्रदेश में देवीलाल-चंद्रशेखर के संयुक्त उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष बन गये।

लेकिन राजनीतिक महाभारत की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के हिस्से में आयी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल के बीच तीन घंटे लंबे सहभोज की खुशबू और 'सात सदस्यीय समिति' के जन्म की बधाइयां।

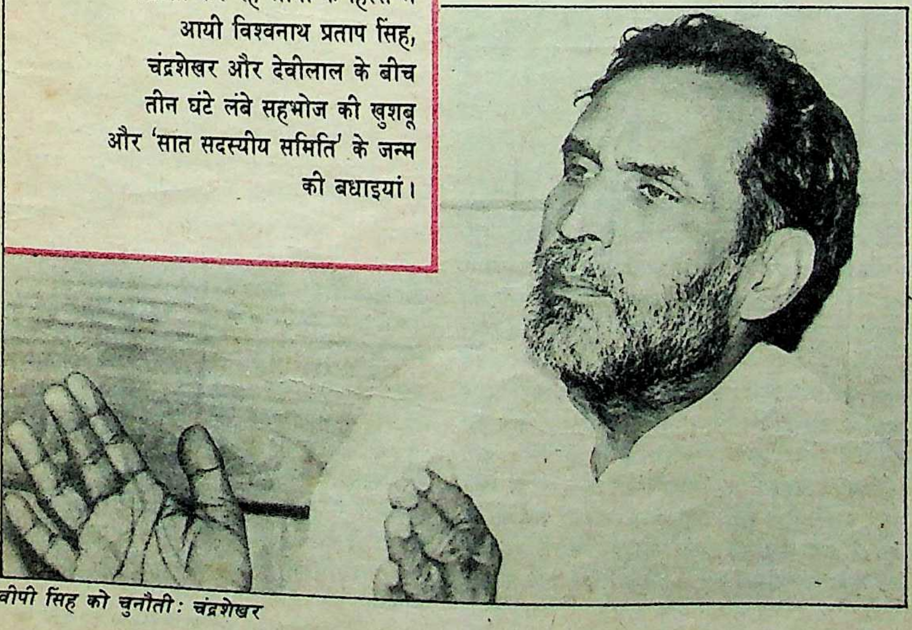

वीपी सिंह को चुनौती : चंद्रशेखर

नतीजतन ज्यादा बड़ा भाग देवीलाल के हिस्से में आया। इसलिए बाद में हुई बैठक में चौधरी देवीलाल ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल का पूरा संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने में काफी समय लगेगा और चुनाव सिर पर है, इसलिए राज्यों में अध्यक्षों की अगुआई में संसदीय दल नेता, राज्य महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्षों की चार सदस्यीय समितियां उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दिल्ली में जनता दल के संसदीय बोर्ड को भेजें, ताकि संसदीय बोर्ड जल्द-से-जल्द उम्मीदवारों का चयन पूरा कर उन्हें अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी तैयारी में जुटने का हुकुम दे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सहित दल के बाकी सभी राष्ट्रीय नेता दल के संगठनात्मक झगड़ों से मुक्त होकर देश भर में धुआंधार दौरों पर निकल जायें।

हरियाणा की जमीन से कांग्रेस का जनाजा उठानेवाले इस बुजुर्ग किसान नेता की यह राय जहां चुनावी रणनीति के तौर पर पूरी तरह सही थी, वहीं इसके पीछे चौधरी देवीलाल के मन में बैठा भय भी काम कर रहा था। देवीलाल के दरबार में पहुंचनेवाली एक लाबी ने उनके कान में यह फूंक दिया था, "बेहतर हो कि आप अभी टिकट तय करवा दीजिये, क्योंकि राजा का कोई भरोसा नहीं है। फिर जनता दल के अध्यक्ष के रूप में तकनीकी तौर पर तो टिकट देने का अधिकार वीपी सिंह के ही हाथ में है। यदि उन्होंने ऐन वक्त पर पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला एक तरफ रख कर अपने लोगों को टिकट बांट दिये, तो क्या होगा ?" बताते हैं उस विद्वान सलाहकार को उस समय तो देवीलाल ने जोर से डपट दिया, पर उसकी बात देवीलाल पर असर छोड़ गयी थी।

बौखलाहट : पर विश्वनाथ प्रताप सिंह से इस संबंध में बात करने पर उनके फौरन तैयार हो जाने से चौधरी देवीलाल पुनः आश्वस्त हो गये। उधर देवीलाल-चंद्रशेखर के बीच तालमेल बनने की खबर से विपक्षी राजनीति में 'किंग मेकर' की गलतफहमी पालनेवाली एक पूरी-की-पूरी शक्तिशाली लाबी में भगदड़ मच गयी। भारतीय जनता पार्टी से करीबी संबंध रखनेवाली यह लाबी अभी तक यह मान रही थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल दोनों उनके हाथ में हैं। देवीलाल को हाथ से निकलते देख 'भारतीय विपक्ष के इन विधाताओं' का बौखलाना स्वाभाविक था। चौधरी देवीलाल को इस लाबी के 'बुद्धिजीवियों' ने फिर समझाया, "जनता विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर ही वोट देगी न कि चंद्रशेखर के। ऐसी हालत में विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे रखकर असली नेता तो आप ही होंगे।" चुनावी रणनीति के पुराने खिलाड़ी देवीलाल पर इन बातों का क्या असर पड़ा यह कहना कठिन है, पर इस भागदौड़ का यह नतीजा जरूर निकला कि देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बार फिर ज्यादा नजदीक आ गये। जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगा कि देवीलाल के मन में चंद्रशेखर के लिए पैदा हुआ मोह खतम हो गया है और वे फिर से पूरी तरह उनके साथ हैं, उन्होंने १६ मई '८६ को रघुनाथ झा को हटाने का आदेश जारी कर दिया।

वीपी सिंह की तानाशाही : रघुनाथ झा को हटाकर रामकृष्ण हेगड़े के उम्मीदवार रामसुंदर दास को बैठने के आदेश से चंद्रशेखर का बुरी तरह बौखला जाना स्वाभाविक था। अगले ही दिन उन्होंने चौधरी देवीलाल से दो घंटे बातचीत की। "क्या वीपी सिंह ने इस बाबत आपसे बात की थी ?" चंद्रशेखर ने मिलते ही सीधा सवाल पूछा। देवीलाल का कहना था कि रघुनाथ झा को उनसे पूछकर नहीं हटाया गया है। फिर क्या था, चंद्रशेखर को मौका मिल गया। उनका तर्क था कि रघुनाथ झा को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चुना गया था। अतः पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति के बिना विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें कैसे हटा सकते हैं ? दो घंटे चली इस बातचीत में चंद्रशेखर को दो बातें साफ पता चलीं। एक, रघुनाथ झा को हटाये जाने के बारे में देवीलाल को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। दो, देवीलाल इस मुद्दे पर सीधे मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। अंत में चंद्रशेखर ने देवीलाल के सामने एक प्रस्ताव रखा, "चूंकि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के आदेश को मनमर्जी

पलटा है, इसलिए मैं इस संबंध में आपको एक विरोध पत्र दे रहा हूं। इस पर आगे आप क्या कर पायेंगे यह आप जानिये।" इसके बाद ही चंद्रशेखर द्वारा लिखी गयी एक सीलबंद चिट्ठी देवीलाल को सौंप दी गयी। २१ मई को चंद्रशेखर बुरी तरह बौखलाये हुए थे। सुबह से ही वे अपने सचिवों और निकटवर्ती सलाहकारों पर रह-रहकर बेबात बिगड़ उठते थे। उसी दिन शाम को सुबोध कांत चंद्रशेखर से मिलने आये। वे चंद्रशेखर को यह बताने आये थे कि वे २३ मई से शुरू होनेवाले बंगलौर अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हैं। इस बात का पता चलते ही कि सुबोध बंगलौर जा रहे हैं, चंद्रशेखर बोले, "जाकर अपने राजा से कह देना कि उसने इस बार मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी है। जब किसी मर्द के स्वाभिमान पर हमला हो, तो उसे या तो अपनी पूरी ताकत से उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, या कहीं जाकर डूब मरना चाहिए।" उसी दिन उन्होंने अपने सचिव गौतम को आदेश दिया कि वह उनके लिए अहमदाबाद और बंबई के टिकट बुक करायें। अहमदाबाद में चिमनभाई पटेल की बिटिया की शादी थी। पर यह यात्रा सिर्फ अपने एक पुराने परिचित की बिटिया की शादी पर पहुंचने की पारिवारिक औपचारिकता भर नहीं थी। चंद्रशेखर अपनी इस यात्रा के दो बड़े तथा महत्वपूर्ण मिशन तय कर चुके थे। एक, प्रभाकर मेहता से मिलना, जिन्होंने हफ्ते भर पहले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की बाबत जेपी की चिट्ठी जारी की थी। दूसरी, अपनी विरोधी एक्सप्रेस लाबी के महाशत्रु लाला धीरूभाई अंबानी से मिलना।

उल्लेखनीय है कि गुपचुप चालें चल रहे चंद्रशेखर अब खुलकर हमला बोलेंगे, इस बात का अंदाज तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक हफ्ते पहले ही हो गया था, जब अचानक अहमदाबाद से १५ मई को प्रभाकर मेहता ने सिंह की बाबत जयप्रकाश नारायण की चिट्ठी जारी की थी। इसके फौरन बाद ही सिंह ने बिहार में रघुनाथ झा को हटाने का हुकुम जारी कर पेशबंदी कर ली थी, ताकि यदि जेपी के खत का मामला जोर पकड़े, तो वे पहले ही कह सकें कि झा को हटाये जाने से नाखुश चंद्रशेखर समर्थक कांग्रेस और धीरूभाई अंबानी द्वारा जारी कारवायी गयी इस फर्जी चिट्ठी का बहाना बनाकर पार्टी तोडना चाह रहे हैं।

चंद्रशेखर का तुरुप: दूसरी ओर जेपी की चिट्ठी प्रकाशित होने के तुरंत बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा और आक्रामक रुख अपनाने पर चंद्रशेखर ने सीधे अपनी तुरुप चाल खेली। जब जनता दल के सभी नेता बंगलौर अधिवेशन में व्यस्त थे, तो उस समय चंद्रशेखर बंबई में तांत्रिक चंद्रास्वामी के साथ धीरूभाई अंबानी से बात कर रहे थे। इस संबंध में चंद्रशेखर का कहना है कि वे २४ मई को बंबई के ओबेराय होटल में चंद्रास्वामी से बात करने गये थे। उनके अनुसार, "मैं धीरूभाई से मिलने नहीं गया था। मेरी यात्रा का मकसद चिमनभाई पटेल की बिटिया की शादी में शामिल होना था। रास्ते में मैं प्रभाकर मेहता से भी मिलने गया। दरअसल मुझे पता चला था कि चिट्ठी छपने के बाद से एक्सप्रेस ग्रुप वाले उस बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हैं। प्रभाकर मेहता से मुलाकात के बाद ही चंद्रास्वामी का सचिव मेरे पास यह पैगाम लेकर आया कि चंद्रास्वामी मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं खुद ही चल कर मिल लेता हूं। मैं रात को ओबेराय होटल में चंद्रास्वामी के कमरे पर पहुंचा। दस मिनट रुका और लौट आया। बस इतनी सी बात थी। पर एक्सप्रेस वाले प्रभाकर मेहता के घर से ही मेरे पीछे जासूसी कर रहे थे। संभव है मेरे जाने के बाद ओबेराय में लिफ्ट से उन्होंने धीरूभाई अंबानी को उतरते देखा हो, जिसे उन्होंने देश भर में ऐसा फैला दिया जैसे चंद्रशेखर धीरूभाई से मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे।" "पर क्या चंद्रास्वामी के कमरे में धीरूभाई अंबानी पहले से मौजूद नहीं थे?" इस सीधे सवाल को अनसुना करते हुए वे कहते हैं, "चंद्रास्वामी को मैं आज से नहीं बीस साल पहले से जानता हूं जब वे दिल्ली में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। उसी चंद्रास्वामी को डेढ़ साल पहले तक जब रामनाथ गोयनका एंड कंपनी अपने कंधे पर लिये घूम रही थी तब तक ठीक था। आज यदि मैं उससे मिल लिया, तो मैंने जैसे कोई पाप कर दिया।" चंद्रशेखर उत्तेजित होते हैं और पुनः धीरूभाई अंबानी के—सवाल को बीच में ही काट कर कहते हैं, "मैंने कहा मैं धीरूभाई अंबानी से मिलने नहीं गया था। यदि मैं उनसे मिलने जाऊंगा, तो मुझे सार्वजनिक रूप से यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा। मेरा राजनीतिक दामन ऐसा नहीं है कि किसी के मिलने भर से कलंकित हो जायेगा।"

एक दूसरे का इस्तेमाल करने के मंसूबे: चंद्रशेखर और देवीलाल

पर मुलाकात की असलियत, लाख छुपाने के बावजूद, जल्द ही चंद्रशेखर के समर्थकों और शत्रुओं तक पहुंच गयी। ओबेराय होटल में रात नौ बजे से साढ़े नौ बजे तक हुई इस मुलाकात में चंद्रशेखर, चंद्रास्वामी और धीरूभाई अंबानी के अलावा चंद्रास्वामी के सचिव कैलाशनाथ अग्रवाल उर्फ मामाजी, मुकेश अंबानी और राज सलगांवकर भी मौजूद थे। चंद्रशेखर की धीरूभाई अंबानी से मुलाकात के संबंध में हासिल एक सूचना और भी महत्वपूर्ण है। चंद्रास्वामी के एक नजदीकी सूत्र के अनुसार, "धीरूभाई अंबानी से मुलाकात की सूचना खुद चंद्रशेखर ने ही चंद्रास्वामी के सूत्रों के जरिये इस तरह से लीक करवाई थी कि एक्सप्रेस समूह को ऐसा लगे कि उन्हें जैसे कोई बडी खबर हाथ लग गयी है।" इसकी बावत उनका तर्क है कि यदि चंद्रशेखर को धीरूभाई अंबानी से बात ही करनी होगी या वे आपस में बात करते होंगे, तो उसके बीसियों गोपनीय तरीके हो सकते हैं। बंबई में ओबेराय होटल में जाकर दोनों को यह नाटक करने और फिर इसके बाद मुलाकात के मुद्दे पर चंद्रशेखर को 'हां-ना' नुमा गोलमाल जवाब देकर मुद्दे को जिंदा रखने की क्या जरूरत होगी?

बहरहाल, यह मुलाकात एक 'नाटक' थी या 'षड्यंत्र' और मुलाकात की खबर एक्सप्रेस ग्रुप ने खुद जासूसी कर हासिल की थी या उन तक बेहद सतर्कता से खुद चंद्रशेखर-चंद्रास्वामी ने ही लीक करवा दी थी, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि उस मुलाकात के नतीजे साफ थे। एक, मुलाकात की खबर सुनते ही एक्सप्रेस समूह और विश्वनाथ प्रताप सिंह गुट का बुरी तरह

बौखला उठना। मुलाकात उनके लिए चंद्रशेखर की सीधी चुनौती थी कि "कल तक के तुम्हारे सबसे बड़े मित्र चंद्रास्वामी और सबसे बड़े शत्रु धीरूभाई अंबानी दोनों मेरे साथ हैं।"

विरोध का नया रूप: वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात के फौरन बाद दिल्ली के राजनीतिक हलकों में एक अफवाह तेजी से फैली या फैलायी गयी। अफवाह थी—धीरूभाई ने हरियाणा सरकार को गिराने के लिए पचास करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। ऐसे में हरियाणा सरकार अब कुछ ही महीने की मेहमान है। अफवाह किसी ने भी फैलायी हो, पर एक्सप्रेस समूह और चंद्रशेखर गुट दोनों ही इसे अपनी तरह से भुनाने में लगे थे। एक्सप्रेस समूह देवीलाल को यह समझाने में जुट गया कि यदि अब भी चंद्रशेखर को दल से न निकाला गया, तो बहुत बड़ी भूल होगी। वहीं चौटाला सहित दूसरे गुट का मानना था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और एक्सप्रेस के झगड़े में देवीलाल चंद्रशेखर से दुश्मनी मोल लें।

राजनीति के पुराने घाघ चौधरी देवीलाल ने इस मौके पर गेंद उलटे वीपी सिंह की पारी में यह कहकर डाल दी, "जैसा दल के सभी नेता तय करें, वही फैसला हो।" इसके बाद ही एक्सप्रेस समूह के लोगों ने जहां अजीत सिंह से लेकर जयपाल रेड्डी और मधु दंडवते आदि को इसके लिए तैयार करना शुरू किया (हेगड़े तो पहले से ही तैयार बैठे थे), वहीं ३ जून को देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ शिमला दौरे के लिए उड़ गये। चार जून को कुल्लू में व्यास नदी के किनारे देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच चंद्रशेखर के मुद्दे पर तीन घंटे लंबी बातचीत हुई और अगले दिन दोनों नेता दिल्ली लौट आये। पांच जून को राजधानी के राजनीतिक हलके में चर्चा शुरू हो गयी थी कि देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से चंद्रशेखर के मामले पर सात दिन इंतजार करने को कहा है। देवीलाल के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार, "चौधरी साहब ने वीपी सिंह से कहा है कि वे एक हफ्ते में सब ठीक कर देंगे। यदि हफ्ते भर में कोई हल न निकला, तो वे और दल के बाकी नेता जैसा चाहें वैसा करें।" इस यात्रा में ही यह भी तय हुआ कि वीपी सिंह चंद्रशेखर द्वारा देवीलाल को रघुनाथ झा के मसले पर लिखे विरोध पत्र (जिसे देवीलाल अपने नोट के साथ वीपी सिंह को भेज चुके थे) के जवाब में एक पत्र लिखेंगे। इसमें वे यह मानेंगे कि चंद्रशेखर उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली लौटकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसा एक खत देवीलाल को भिजवा दिया।

किंग मेकर का गणित: उधर पांच जून को ही देवीलाल के दिल्ली पहुंचने पर जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी, एक्सप्रेस के सलाहकार गुरुमूर्ति अजीत सिंह को साथ लेकर देवीलाल से मिलने पहुंचे थे। मकसद साफ था कि कुल्लू-शिमला यात्रा में, "आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की राय जान चुके होंगे। रामकृष्ण हेगड़े, मधु दंडवते और जयपाल रेड्डी वगैरह भी हमारे साथ हैं और अब अजीत सिंह गुट भी हाजिर है।" देवीलाल ने तीनों की बातें सुनीं और यह कहकर अपने पत्ते छिपाये रखे, "हफ्ते भर देख लेते हैं। कुछ हो जाये तो ठीक है, वरना पार्लियामेंट्री बोर्ड जो समझे वह तय कर ले।" इस समय तक चंद्रशेखर को पार्टी से निकाले जाने के लिए बन चुकी हवा को देखने के बाद देवीलाल का सतर्क होना स्वाभाविक था। इस संबंध में जनता दल की आंतरिक स्थितियों से वाकिफ लोगों का मानना है, "निश्चय ही राजनीति का यह बुजुर्ग खिलाड़ी यह कभी नहीं पसंद करता कि चंद्रशेखर से कितनी ही नापसंदगी के बावजूद उन्हें जनता चल से निकाल दिया जाये। और-तो-और यदि चंद्रशेखर खुद भी जनता दल छोड़कर जा रहे होते, तो देवीलाल इस समय उन्हें हाथ पकड़ कर खुद वापस ले आते। क्योंकि जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर दोनों की शत्रुतापूर्ण उपस्थिति ही वह आदर्श स्थिति होगी जिसमें दोनों के मध्य संतुलन बनाकर देवीलाल विपक्षी राजनीति के भीष्म-पितामह की अपनी भूमिका कायम रख सकते थे।"

यही वजह थी कि पांच जून को ही अजीत सिंह से मुलाकात करने के बाद देवीलाल ने सीधे चंद्रशेखर से संपर्क किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की चिट्ठी उन्हें दिखा दी गयी। चिट्ठी गोपनीय रखी गयी थी। पर अगले ही दिन उस चिट्ठी की भाषा और फिर उसे छपवाने की घटना से और भड़क उठे और छह जून को वे उड़ीसा के लिए रवाना हो गये।

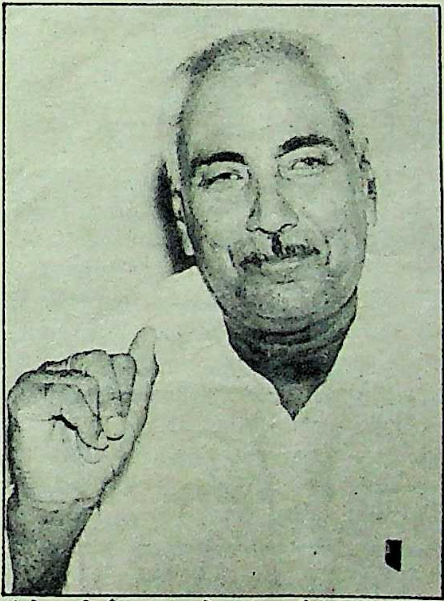

चंद्रशेखर से निकटता: ओमप्रकाश चौटाला

असफल प्रयास: उड़ीसा में चंद्रशेखर के छह-सात और आठ जून को कार्यक्रम थे। नौ जून को जनता दल की उदयपुर में जनसभा थी। देवीलाल ने जनता दल नेताओं को भरोसा दिलाया था कि नौ जून को चंद्रशेखर उदयपुर में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भाषण एक ही मंच पर देंगे। आठ जून की रात को चंद्रशेखर दिल्ली नहीं लौटे। तब देवीलाल ने चंडीगढ़ से दिल्ली शरद यादव के यहां देर रात आठ बजे फोन किया कि मालूम करो चंद्रशेखर कहां हैं? उन्हें हर हालत में कल उदयपुर पहुंचना है। यदि इसके लिए स्टेट प्लेन भी भेजना पड़े, तो वे तैयार हैं। चंद्रशेखर के यहां से पता लगा कि उड़ीसा से उन्होंने कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना लिया है। शरद यादव ने कलकत्ता फोन किया। पर आठ जून की रात फ्लाइट रद्द हो जाने के चलते चंद्रशेखर उस रात उड़ीसा में ही रुक गये। इसलिए कलकत्ता में भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। नतीजतन नौ जून को चंद्रशेखर उदयपुर नहीं पहुंचे। देवीलाल का वायदा वीपी सिंह गुट को झूठा लगा। उधर नौ जून को चंद्रशेखर ने ज्योति बसु से लंबी बातचीत की। दिल्ली लौटकर चंद्रशेखर ने प्रेस कांफ्रेंस कर सीधे विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्यशैली को चुनौती दे डाली। इसके बाद सभी को साफ लगने लगा कि अब समझौते के कोई आसार नहीं हैं।

११ जून को हरिकेश बहादुर समेत तीन चंद्रशेखर समर्थकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गयी। १२ जून की सुबह देवीलाल द्वारा निर्धारित सात दिनों की मोहलत का आखिरी दिन था। देर दोपहर तक चंद्रशेखर-वीपी सिंह के बीच सुलह का कोई संकेत न पाने के बाद तो जैसे जनता दल के एक-दूसरे गुट और एक्सप्रेस समूह के लोगों को पक्का भरोसा हो गया कि अब चंद्रशेखर का निकाला जाना तय है। उसी दिन शाम को 'जनसत्ता' के संपादक प्रभाष जोशी चंद्रशेखर को निशाना बना अपने खौलते हुए लेख टाइप करवा रहे थे, ताकि लेख देर रात तैयार होकर अगले दिन छापा मशीनों पर चढ़ जाये। इस मोर्चे पर तैनात लोगों का मानना था कि चौदह जून की सुबह-सुबह लेख जब देश भर में पढ़ा जा रहा होगा, ठीक उसी समय जनता दल के संसदीय बोर्ड में चंद्रशेखर को दल से निकालने की कार्रवाई पूरी हो रही होगी। यानी इस तरह चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन के ताबूत में ठोंकने के लिए आखिरी कील पैनी कर ली गयी थी।

अगले समझौते की प्रतीक्षा: पर ठीक उसी समय १२ जून की रात को देवीलाल सोहना गेस्ट हाउस में चंद्रशेखर से बैठे अगली रणनीति बना रहे थे। दोनों नेताओं के बीच देर रात ढाई घंटे लंबी बातचीत का नतीजा था कि अगले दिन देवीलाल सुबह-सुबह विश्वनाथ प्रताप सिंह से लंबे समझौते फार्मूले को अंतिम रूप दे रहे थे। अगले दिन चंद्रशेखर को निकालने की जगह तीनों नेता तीन घंटे तक बैठ आपस में भोजन कर रहे थे। और संसदीय दल की बैठक एक घंटे बाद सात सदस्यीय समिति को जन्म देने के लिए शुरू हो रही थी। युद्ध का एक चक्र पूरा हो चुका था। अब अगले की प्रतीक्षा थी। और सिर्फ एक पखवाड़े के अंदर ही यशवंत सिन्हा के इस्तीफे के साथ अगले दौर की फिर शुरुआत हो गयी जो अभी जारी है, फिर अगले समझौते तक के लिए।

—पुनीत टंडन

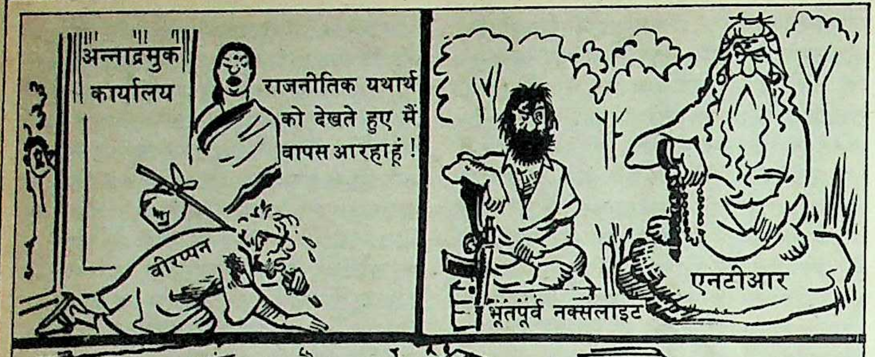

व्यंग्यकार : आरके लक्ष्मण
सौजन्य : टाइम्स आफ इंडिया

क्या हम कूढ़मगज हैं ?

लगभग ३० साल पहले की बात है, जब मुझे पश्चिम बर्लिन में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला। इस सम्मेलन में कुछ प्रवुद्ध अमरीकियों, ब्रिटेनवासियों और जर्मन लोगों के बीच इस विषय पर बहस हो रही थी कि ब्रिटिश उपनिवेश से भारत किस तरह प्रभावित हुआ। काफी खींचतान के बाद लोग इस बात पर एकमत हुए कि यदि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश न बनाया होता, तो आज इतना बड़ा अखंड भारत देखने को न मिलता। यानी हमारा देश छोटी-छोटी सामंती इकाइयों में विखंडित होकर रह जाता। इसके अलावा ब्रिटिश प्रभावों का आकलन करते हुए वे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत ब्रिटिश शासन के कारण ही पश्चिमी उदारवादी राजनीतिक विचारधारा के संपर्क में आया। यही नहीं, इसी बहस-मुबाहिसे के दौरान यह मुद्दा भी उठा था कि केवल हमारा देश ही अविकसित नहीं, बल्कि भारतवासियों का दिमाग भी अविकसित है। किंतु काफी बहस के बाद भी विदेशी इस मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाये थे। लेकिन यह सवाल आज तक मेरे दिमाग में गूंजता रहता है और बर्लिन सम्मेलन की याद दिलाता रहता है।

बर्लिन सम्मेलन के बहस-मुबाहिसे में उपस्थित होने के बाद मुझे इस बात का अहसास हुआ था कि दुनिया के उच्च शिक्षित लोग हमारे बारे में कितनी खराब धारणा रखते हैं। जाहिर है, विदेशियों का यह नजरिया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारतवासी भी बहुत पिछड़े दिमाग के लोग हैं, कोई मामूली बात नहीं। जब मैंने पहले-पहल इस बात को सुना था, तो आश्चर्य में पड़ गया था, किंतु कर क्या सकता था ? ऐसी स्थिति में अपनी नजरों में ही गिरने से बचने का एक ही उपाय था कि मैं खराब धारणा रखनेवालों के लिए ही गलत नजरिया बनाता। मैंने वैसा ही किया। बर्लिन सम्मेलन से लौटने के बाद मैंने यह नजरिया बनाया कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, वे खुद काफी पिछड़े हुए थे और औपनिवेशिक प्रभाव से ग्रस्त थे, किंतु अफसोस इस बात पर है कि कुछ सालों के बाद मुझे अपना यह नजरिया बदलना पड़ा।

इस्रायल की मिसाल : मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९७२ में जब मैं अमरीका से वाया तेलअवीव भारत लौट रहा था, तो मैंने हवाई जहाज से इस्रायली क्षेत्र का जायजा लिया था। इतनी ऊंचाई से देखने के बावजूद इस्रायली क्षेत्र की हरियाली साफ नुमायां थी जो इस बात का अहसास कराती थी कि इस्रायल में काफी विकास हुआ है। यानी शुरू के दौर में पश्चिमी ताकतों ने इस्रायल की जो मदद की, उसका इस देश ने भरपूर इस्तेमाल किया। उल्लेखनीय है कि शुरू के २० साल तक तो इस्रायल अमरीकी तथा पश्चिमी वित्तीय तथा सैनिक सहायता के बलबूते जिंदा रह सका, किंतु उसने मिलनेवाली हर मदद का सही इस्तेमाल करने में आनाकानी नहीं की, नतीजतन शुरू में तो पश्चिमी ताकतों पर निर्भर रहा, किंतु कालांतर में आत्मनिर्भर हो गया। आज इस्रायल सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा में ही सक्षम नही है, बल्कि अपनी शर्तों पर अरब देशों को झुकाने का भी बाहुबल रखता है। यही नहीं, विश्वयुद्ध के बाद इस्रायल ही ऐसा देश है, जिसने दूसरों के क्षेत्र पर कब्जा किया और आज तक उस पर नियंत्रण किये हुए है। उसकी इस हरकत पर लोग उंगली तो उठाते हैं, किंतु उससे टकराने का साहस नहीं जुटा पाते। इसके अलावा इस्रायल ने अपने अस्तित्व के इस छोटे से दौर में दूसरे देशों के परमाणु केंद्रों पर बिना युद्ध की घोषणा किये हुए हमले किये, किंतु किसी की हिम्मत न हुई जो उसे उसकी बेजा हरकतों से रोकता।

कौन नहीं जानता कि कैंप डेविड समझौते की बातचीत के दौरान जब अमरीका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अरब-इस्रायल संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभायी थी, तो उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को समझाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई थी, किंतु इस्रायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिनाशेम बेगिन को समझाना कार्टर के लिए टेढ़ी खीर बन गया था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने दूसरों की मदद का सही इस्तेमाल किया और जिन्होंने किसी मदद का सही इस्तेमाल नहीं किया, उनके विचारों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। पेट्रोडालर के सहारे फले-फूले देशों के उत्थान और पतन की गाथा आखिर इसी बात के तो संकेत देती है कि विकास सिर्फ धन-दौलत के बूते ही नहीं होता। उसके लिए दृष्टि और नीतियों की जरूरत होती है।

पश्चिम को चुनौती : उल्लेखनीय है कि १९७३ में जब अरब राष्ट्रों को अपनी तेल संपदा की ताकत का अहसास हुआ, तो वे एकजुट हुए और तेल की कीमत दो डालर प्रति बैरल बढ़कर दस डालर प्रति बैरल हो गयी। जाहिर है, इस बढ़ोतरी के फलस्वरूप अरब देशों में अथाह दौलत का इकट्ठा होना अस्वाभाविक था। किंतु तभी पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों ने इस बात का अहसास किया कि अरब राष्ट्रों ने तेल की कीमत बढ़ाकर उनकी समृद्धि को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। नतीजतन विश्व भर में बड़े पैमाने पर तेल की खोज शुरू हो गयी। अरब देशों द्वारा बढ़ायी गयी तेल की

कीमत का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने का निर्णय किया।

उल्लेखनीय है कि मानव इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में दौलत इतने कम समय में किसी क्षेत्र में नहीं पहुंची, जितनी उस दौरान खाड़ी देशों में इकट्ठा हुई।

भारतीय होड़: अरब देशों द्वारा बढ़ायी गयी तेल की कीमत का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। बंबई में डाक्टरों तथा दुकानदारों ने अरबी भाषा में बोर्ड लगवाने शुरू कर दिये और अरबी सीखनी शुरू कर दी। स्थिति यह हुई कि मामूली-से-मामूली काम करनेवाले लोगों ने अरबी बोलनी सीख ली। यही नहीं, सरकारों ने भी पेट्रोडालर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया। यहां पर इस बात को याद रखना जरूरी है कि जब भारतीय अरबी भाषा को गले लगा रहे थे, उस वक्त पश्चिमी देश अपने प्रभाव को पुन: कायम करने पर विचार कर रहे थे। पेट्रोडालर द्वारा पैदा की गयी विषम परिस्थिति से अपने आपको मुक्त रखना ही उनका परम ध्येय था। इसी वक्त ईरान-इराक के बीच युद्ध छिड़ गया और पश्चिमी देशों ने हथियार-आपूर्ति का काम शुरू कर दिया। यानी समय आ गया था, जब पश्चिम अपनी कूटनीति के सहारे आहिस्ता-आहिस्ता पेट्रोडालर के हंगामे को समाप्त करने में अपने को सक्षम पा रहा था।

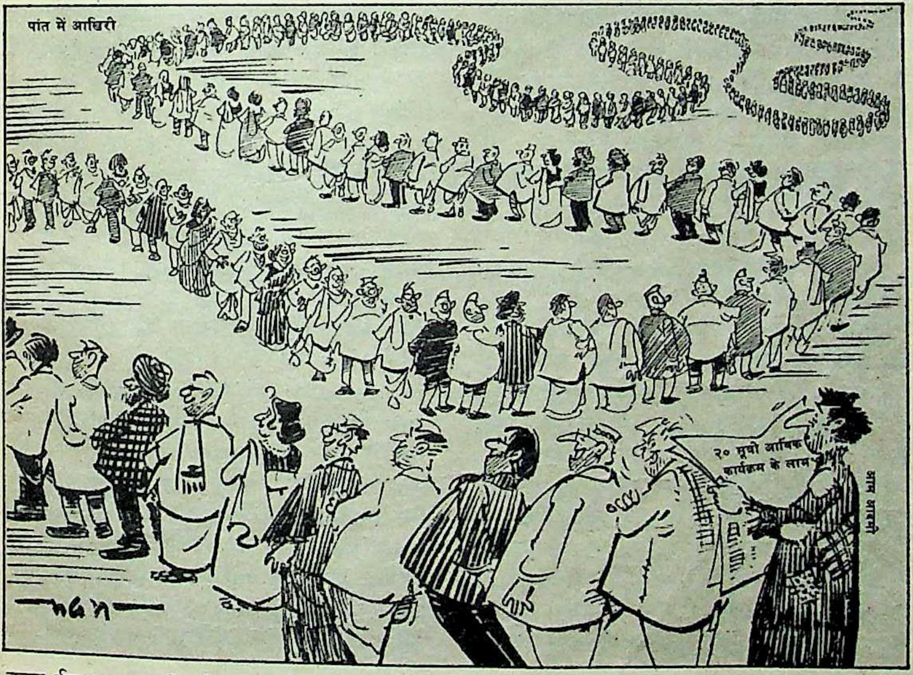
पांत में आखिरी
२० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभ
आम आदमी

परास्त होते खाड़ी देश: ईरान-इराक युद्ध आठ वर्षों तक जारी रहा। इस बीच भी दोनों देशों ने तेल का उत्पादन जारी रखा, किंतु तेल से होने वाली आमदनी हथियार खरीदने में इस्तेमाल होती रही। अब युद्ध समाप्त हो चुका है। इस बीच पश्चिम देशों ने अपनी तेल की खपत घटाकर नगण्य के बराबर कर दी है। यानी अब कोई तेल-उत्पादक राष्ट्र उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। यही वजह है कि फरवरी '८९ में भी तेल की कीमत वही रही जो पंद्रह वर्ष पहले थी—लगभग दस डालर प्रति बैरल—जबकि मुद्रास्फीति आदि के प्रभाव के कारण इसमें बढ़त होनी चाहिए थी। यही नहीं, ईरान और इराक की अर्थव्यवस्था तो आठ साल के युद्ध में एसी चरमरा गयी है कि अगले कुछ सालों तक उसे कम दाम पर ही तेल बेचना पड़ेगा, ताकि युद्ध से हुए नुकसान की भरपायी करने में कोई बाधा न आये। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि इन देशों ने तेल की कीमत बढ़ाकर जो धन उगाहा था, वह दुबारा वहीं पहुंच गया जहां से आया था।

गलती का अहसास: आज शेखों को इस बात का अहसास हो गया कि आसानी से कमायी गयी दौलत का दुरुपयोग करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उस दौलत से उन्होंने जो कुछ भी खरीदा या बनाया अथवा ऐशो-आराम के लिए जो कुछ इकट्ठा किया, उससे उनकी भविष्य की जरूरतें पूरी होनेवाली नहीं। फिर अदनान खशोगी जैसी लोगों के हाथों पड़कर हुस्न और हथियार खरीदकर उन्हें क्या मिला? सिर्फ झूठी शानोशौकत ही अस्तित्व के लिए काफी नहीं। आज अरब राष्ट्रों की या शेखों की जो स्थिति है, वह इस बात का बोलता हुआ सुबूत है कि अविकसित दिमाग द्वारा हड़पी गयी हैसियत और दौलत अस्थायी होती है, जिसे कालांतर में विकसित स्थिति वाले अपनी कूटनीति के जरिये वापस ले लेते हैं। आज स्थिति यह है कि पश्चिम ने अपनी पुरानी हैसियत तो वापस पायी ही साथ में वह दौलत वापस ले ली जो अचानक तेल की कीमत बढ़ने तथा विकल्प का अभाव होने के कारण खाड़ी देश पहुंची थी।

हमारी स्थिति: हमने अपने देश के लिए ब्रिटिश हुक्मरानों से प्रभावित होकर संघीय, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया, जिसमें स्वतंत्रता तथा समता के सिद्धांत पर विशेष जोर दिया गया। इस संविधान के बावजूद हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार के प्रमुख जब केरल पहुंचे, तो उन्होंने मुस्लिम जिला बनाया, ताकि मुस्लिम लीग खुश हो जाये और उन्हें केरल की हुकूमत में साझेदारी मिल जाये, जबकि नेहरू को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने तथा उनकी मर्यादाओं को कायम रखने का प्रतीक माना जाता है। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने अपने कार्यालय के दौरान इस बात पर ध्यान दिया कि पंडित नेहरू के जमाने में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी की गयीं, उन्हें शक्तिहीन कर दिया जाये। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकतंत्र का उन्होंने इस हद तक गला घोंटा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति न होकर उनके (श्रीमती गांधी) हाथ में सत्ता तथा शक्ति इकट्ठा करने के प्रति हो जाये।

विरोधाभास: इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय संविधान तो लोकतंत्र की बात करता है, किंतु हमारे देश की अग्रणी राजनीतिक पार्टियों तक में—वामपंथी पार्टियों को छोड़कर जिनकी गिनती करना भी अनुचित है, क्योंकि वे मात्र दो राज्यों में ही सफल हैं—अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव है। ऐसा विरोधाभास जल्दी कहां देखने को मिलेगा? सभी राजनीतिक पार्टियां महज मनोनीत लोगों की इकाइयां बनकर रह गयी हैं, क्योंकि पार्टी के नेताओं को अंतर्दलीय चुनाव से अपनी कुरसी खिसकने का भय सताता रहता है। स्थिति यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष भी मनोनीत किये जाते हैं। इसके अलावा आम चुनावों के लिए पार्टी अपने उम्मीदवार जाति तथा धर्म के आधार पर चुनती है। इससे भी ज्यादा विषम स्थिति यह है कि राजनीतिक दल गुंडे-बदमाशों को भी टिकट देने से नहीं हिचकिचाते। उनके समक्ष तो टिकट के बंटवारे का बस यही पैमाना है कि कौन कितना ताकतवर है अथवा उसकी क्या हैसियत है? कौन नहीं जानता कि हाल में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में दो अपराधी गुटों के संघर्ष में हुई एक कांग्रेसी विधायक की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए उसे कांग्रेस की परंपरा का प्रतीक बताया था, जबकि उक्त विधायक कुख्यात

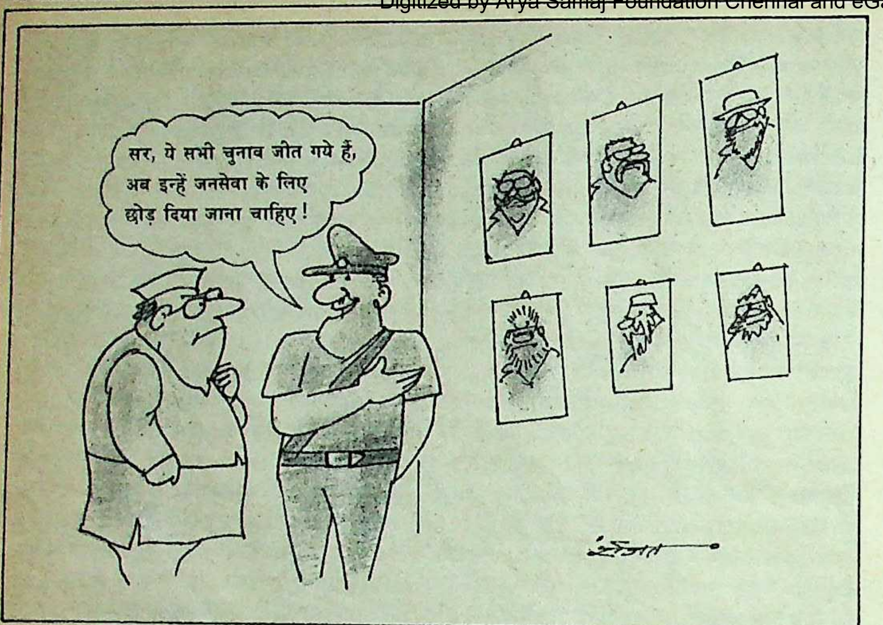
सर, ये सभी चुनाव जीत गये हैं,
अब इन्हें जनसेवा के लिए
छोड़ दिया जाना चाहिए !

अपराधी था, जिस पर कत्ल के कई आरोप थे।

हमारा भ्रम: यही नहीं, हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, जहां की ५० प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीती है और जहां ज्यादातर लोगों को जिंदा रहने के लिए जरूरी २४०० कैलोरी प्रतिदिन उर्जा भी नहीं मिल पाती। कपड़े और आवास की बात तो अलग रही। किंतु हमें इस बात पर फख्र है कि हम 'उत्सव' पर 'उत्सव' मनाते जा रहे हैं।देश की हर दीवार पर महज 'मेरा भारत महान' लिख देने से ही देश महान नहीं हो जायेगा। स्थिति तो यह है कि सभ्य राष्ट्रों की पंगत में हम नगण्य हैं। यदि हम सभ्य राष्ट्रों के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक बेहतर जिंदगी के साजो-सामान से वाकिफ होना पड़ेगा अन्यथा सभ्य राष्ट्रों की चकाचौंध में हम ऐसा खो जायेंगे कि हमारी गरीबी और कमजोरी अपने आप जगजाहिर हो जायेगी। यह तब तक संभव नहीं, जब तक हम इस बात पर शर्म नहीं महसूस करते कि हमारा देश ८० करोड़ की आबादी वाला देश जरूर है, किंतु विश्व-व्यापार में हमारा हिस्सा मात्र ०.५ प्रतिशत है।

अविकसित दिमाग: विकसित दिमाग उसे कहते हैं जो सही फैसला कर सके, जो परिस्थितियों का आकलन कर सके। विकसित दिमाग की पहचान यह है कि वह बहकावों से रक्षा करता है तथा प्रलोभन से बचाता है। मिसाल के तौर पर जब आपका बच्चा आपके साथ बाजार जाता है, तो खिलौने देखकर मचल उठता है तथा बीच बाजार में आपकी बेइज्जती करने पर आमादा हो जाता है। किंतु जब वही बच्चा बड़ा होता है, तो अच्छी-बुरी और जरूरी तथा गैरजरूरी चीजों में फर्क करने लगता है। किंतु अफसोस इस बात पर है कि हम मतदाता हो जाने के बावजूद भी बच्चों-सा दिमाग रखते हैं। इसीलिए तो आसानी से शासकों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे में यदि कोई यह कहता है कि भारतवासियों का दिमाग अविकसित है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है?

निस्संदेह इस बात से हमें दुख पहुंचता है कि हममें सोचने की सामर्थ्य नहीं है, न ही हमारा कोई आत्मसम्मान है। इसकी वजह सिर्फ हमारा अविकसित दिमाग है। यदि हममे सोचने-समझने की ताकत होती या अच्छा-बुरा पहचानने की सामर्थ्य होती, तो हम अपराधियों को विधायक न बनाते तथा माफिया सरदारों को अपना नेता न मानते। अजीब स्थिति है। हमारा प्रधानमंत्री विपक्ष पर यह आरोप लगाता है कि उसमें कातिलों, झूठों और बेईमानों की भरमार है, तो विपक्ष सत्तारूढ़ दल को.ऐसे ही लोगों की जमात बताता है और हम हैं कि चुपचाप बैठे बच्चों की तरह यह तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे में यह कैसे माना जा सकता है कि हमारा दिमाग विकसित है या हम अनुशासन और अनुशासनहीनता के फर्क को समझते हैं।

नाज विश्वविद्यालयों पर: इससे भी बढ़कर मजे की बात यह है कि हमें अपने विश्वविद्यालयों पर नाज है जो हर साल बड़ी तादाद में विकसित दिमाग पैदा कर रहे हैं। किंतु यदि इस मुद्दे पर भी विदेशी विकास को सामने रखा जाये, तो हम पायेंगे कि विश्व समुदाय में हमारी कोई हैसियत नहीं। क्या यह बात इस तथ्य को मनवाने के लिए काफी नहीं कि १९४७ में अमरीका की 'बेल लेबोरेट्री' ने ट्रांसिस्टर बनाया जो आधुनिक इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का आधार बना और हम उसी साल विश्व के आजाद देशों की पंगत में आये। पिछले ४२ सालों में भी हमने जो हाथ-पैर मारा या जो तरक्की की, वह अन्य विकसित देशों की तुलना में नगण्य ही है, मिसाल के तौर पर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को सामने रखें। १९५८ में काफी झगड़े और अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया शांत हुआ। किंतु इतने कम समय में भी उसने कम तरक्की नहीं की। आज स्थिति यह है कि उसने जापान और अमरीका के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। कब और किस वक्त द० कोरिया इन सीमाओं को छोड़कर आगे निकल जायेगा, यह कहा नहीं जा सकता। क्या हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं कि ४२ सालों की आजादी के बावजूद हम विश्व की इलेक्ट्रानिक्स दौड़ में भी अपना स्थान नहीं बना पाये।

देश अमीर, जनता गरीब: निस्संदेह हमारी स्थिति बड़ी ही अजीब है। सच तो यह है कि हमारा देश तो बहुत अमीर है, लेकिन इस देश की जनता बहुत गरीब है। विश्व की कुल आबादी का छठा हिस्सा हमारी आबादी है और हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं। हमें तो सिर्फ इसी बात पर नाज है कि हम विश्व के १० औद्योगिक राष्ट्रों की पंगत में हैं। हमें घमंड है कि विश्व में शिक्षित अभियंताओं और वैज्ञानिकों की तादात के मामलों में भी हम तीसरे नंबर पर हैं। किंतु जब कभी भी तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है, तो हम अपनी स्थिति का अध्ययन उन गरीब, अर्ध विकसित छोटे राष्ट्रों से करते हैं, जिनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं। किंतु हमारे शासक उनकी तुलना में ही अपने को बेहतर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं तथा हमें संतुष्ट कर देते हैं।

इस उक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्धविकसित दिमाग अर्धविकसित लोगों के बीच ही फलता-फूलता है। शायद इस उक्ति पर हमारे शासकों को भी विश्वास है और हम हैं कि हम में सवाल खड़ा करने की योग्यता ही नहीं है। शायद इसीलिए जर्मन दार्शनिक हीगल ने कहा था कि जिस राष्ट्र के लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वह राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम चुपचाप तमाशा देखने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में यदि हीगल का मत सही साबित होता है, तो आश्चर्य की बात नहीं! किंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य विनोबा भावे की खामोशी पर किसी ने टिप्पणी करते हुए उन्हें 'सरकारी संत' कहकर पुकारा था।

—पीसी शर्मा

लेखक परिचय: पीसी शर्मा पेशे से इंजीनियर हैं। पहले भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत रहे, लेकिन पर्यावरण, सामाजिक व मानवीय विषयों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़कर व्यापक यात्राएं कीं। संप्रति वे सलाहकार का कार्य कर रहे हैं।

गैर कांग्रेसी युवकों के साथ पक्षपात : प्योंगयांग समारोह में विश्व युवा प्रतिनिधियों के साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल वासनिक

प्योंगयांग युवा समारोह

युवा कांग्रेस ने फिर नाम कमाया

गत जून में जब विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय युवकों का दल प्योंगयांग विश्व युवा समारोह में भाग लेने कोरिया रवाना हुआ था, तब आम चुनाव के सिर पर खड़े होने के कारण यह उम्मीद की गयी थी कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बेजा हरकतें वहां नहीं करेंगे जो उन्होंने नागपुर अधिवेशन (१९८३), मास्को दिल्ली युवा कांग्रेस समारोह (दिल्ली, १९८२) और मास्को युवा समारोह (१९८५) के दौरान की थीं, लेकिन प्योंगयांग समारोह के जो विवरण प्रकाश में आये हैं, उनसे पता चलता है कि युवा इंकाई यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आये। क्या युवा इंका कांग्रेस का निरंकुश संगठन है?

गत जून में कोरिया में संपन्न विश्व युवा समारोह में भारत की भागीदारी चाहे जो भी रही हो, कांग्रेसी युवकों की हरकतें किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत लज्जाजनक रहीं। ये हरकतें विदेशों में देश की और देश में शासक दल की नाक कटा देनेवाली मानी जा रही हैं। लेकिन शासक दल अपने इन युवकों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नहीं दिखाई देता, तो क्या कांग्रेस-इ ने इन युवकों को कहीं भी, कुछ भी करने की छूट दे रखी है?

टिकट-वितरण : प्योंगयांग में २६ जून से १० जुलाई तक चले १५वें विश्व युवा समारोह में १७७ देशों और ६४ युवा संगठनों के प्रतिनिधिमंडल जुटे थे। उद्देश्य थे—साम्राज्यवाद-विरोधी एकता, शांति और मैत्री और इसके लिए दुनियाभर के युवकों को एक धारा में लाना, भले ही उनमें राजनीतिक-धार्मिक-सांस्कृतिक स्तरों पर अंतर हों। समारोह में शांति और निरस्त्रीकरण, नयी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, युवा छात्रों और बालकों के अधिकारों पर आयोजित ८ वस्तुगत परिचर्चाएं, युवा संसद की बैठकों के जरिये राजनीतिक और सैद्धांतिक मामलों पर बहस, खेल और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे सामूहिक कार्यक्रम—सबके सब अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के गंभीर आयोजन थे। लेकिन वारदात जाहिर करती हैं कि कांग्रेस के लिए यह सब तरह के मजे लेने की खुली आजादी देनेवाला एक राजनीतिक मेला था। देश का प्रतिनिधित्व करनेवाले ३५० युवक-युवतियों में १५० कांग्रेस के थे, ५५-५५ भाकपा-माकपा के, २ तेलुगूदेशम के, १ असम गण परिषद का, १२ जनता दल के और ६ जपा के। झगड़ा प्रतिनिधियों के चयन के साथ ही शुरू हो गया। "कांग्रेस-इ ने देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक जनता दल को पहले प्रतिनिधित्व देना ही नामंजूर कर दिया था—यह कहकर कि चुनाव आयोग ने उसे मान्यता नहीं दी है। अलबत्ता इंका ने जनता पार्टी को जरूरत से ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि वह शासक दल की मददगार पार्टी है", यह बताते हैं, भाकपा की युवा शाखा अखिल भारतीय युवा मोर्चा (एआईवाईएफ) के महासचिव और उक्त समारोह की राष्ट्रीय तैयारी समिति के समन्वयक डी रजा। यही नहीं, जद प्रतिनिधियों को हर स्तर पर हतोत्साहित किया गया, दूसरे प्रतिनिधियों को मिलनेवाले पांच-पांच सौ डालर उन्हें देने से इनकार कर दिया गया, उन्हें विमान की उड़ान का समय तक नहीं बताया गया। अंततः जद प्रतिनिधियों ने विदेश में बीस-बीस डालर से ही काम चलाया, जबकि युवक कांग्रेसियों ने कोरिया में अपने डालर ३० रुपए प्रति डालर की दर से बेचे।

विमान में ऊधम: विमान में शराब पीकर बदमस्त इंकाई युवक चीखे-चिल्लाये, एक-दूसरे से लड़े-भिड़े, विमान परिचारिकाओं को घूर-घूर कर कटाक्ष करते रहे, लगातार घंटी बजाते रहे, अंडबंड बकते हुए अंटशंट चीजें मांगते रहे। तंग आकर विमान अधिकारियों ने घंटी का तार काट दिया और परिचारिकाओं को हटाकर परिचारक तैनात किये। एक बार तो विमान का कप्तान गुस्से में काकपिट से बाहर निकल आया। बोला, "अगर आप लोग शांत नहीं रहते, तो मैं आपको वापस नहीं ले आऊंगा।" युवक कांग्रेस-इ प्रमुख मुकुल वासनिक अपने संगठन और राष्ट्रीय छात्र यूनियन-इ के युवकों की हुल्लड़बाजी के आगे लाचार थे। बददिमागी तब हद तक पहुंच गयी जब एक कांग्रेसी प्रतिनिधि ने पंजाब के एक मार्क्सवादी सिख प्रतिनिधि को धमकाया, "दिल्ली में विमान उतरने दो, हम तुम्हें देख लेंगे।" जब रजा ने इस पर कार्रवाई की मांग की, तो वासनिक 'तत्काल कार्रवाई' का घिसापिटा वायदा दुहरा कर रह गये। कांग्रेसी युवक बेरोकटोक उधम मचाते रहे। विमान के कोरिया की वायु सीमा में प्रवेश करते ही वे सब गंदे गाने अलापने लगे, महिला प्रतिनिधियों पर गंदी फब्तियां कसने लगे और वासनिक और कप्तान की उन्होंने एक न सुनी। जब और कोई रास्ता नहीं रहा, तब सोवियत परिचारकों ने जबर्दस्ती उन्हें उनकी सीटों पर बैठाया।

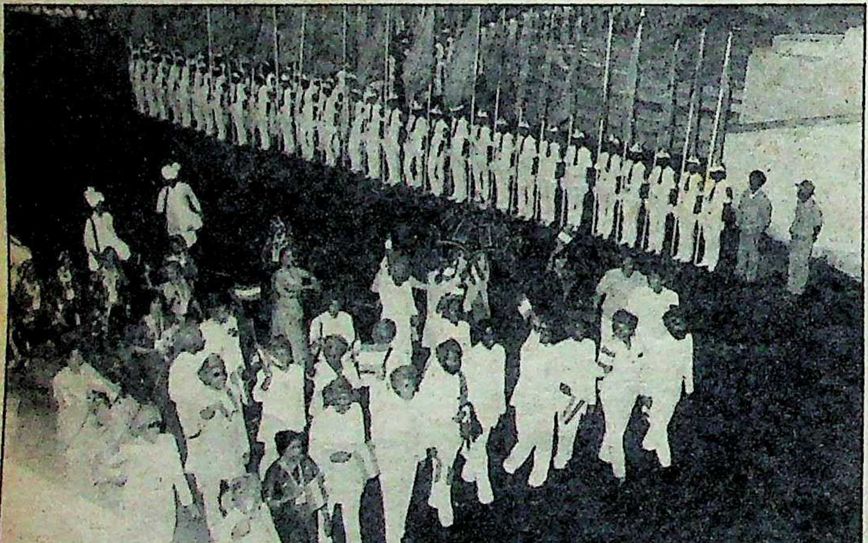

आधा-अधूरा प्रतिनिधित्व: प्योंगयांग समारोह में भारतीय दल

महिलाओं से बदसलूकी: समारोह के दौरान परिचर्चा गोष्ठियां इंकाई युवकों को कतई नापसंद थीं। ऐसे समय वे गोलबंद होकर स्वीमिंग पूल और समुद्र तट का चक्कर लगाते हुए अल्पवस्त्र औरतों के बदन निहारते थे। नृत्य सत्र उन्हें खूब पसंद थे क्योंकि नाचते-नाचते उनको विदेशी लड़कियों को स्पर्श करने और अपनी कुंठा निकालने का मौका मिल जाता था। वे इतावली लड़कियों को 'साली' कहते थे—सोनिया गांधी के रिश्ते से। अकसर वे महिला प्रतिनिधियों की कमीज पर पिन से लगे परिचय पत्र देखने के बहाने उन्हें पिन चुभो देते थे। बात यहां तक बढ़ गयी कि विदेशी लड़कियों ने कांग्रेसियों से बोलना बंद कर दिया और उन्हें फटकारा।

कांग्रेसियों ने अपनी महिला साथी, युवक कांग्रेस की संयुक्त सचिव तरुणा गुर्जर को भी नहीं बख्शा। वे बताती हैं कि एक शाम इंडिया क्लब में निर्धारित कार्यक्रम शुरू होने के एक घंटा पहले अत्तर सिंह टोकस (दूसरे संयुक्त सचिव) ने मेरी तरफ इशारा कर कहा, "राजेश पायलट से मेरा (तरुणा का) नाजायज लफड़ा है। मैंने इसके जवाब में उनके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। टोकस खूंखार जानवर बनकर मुझ पर झपटे, तड़ातड़ छह-सात तमाचे मारे, मेरे ब्लाउज पर हाथ डाला, हाथ पकड़ लिया, छुड़ाने के लिंए मैं देर तक जूझती रही।" बाद में, कड़ा कदम उठाने के बजाय वासनिक ने 'पारिवारिक झगड़ा' कहकर और तरुणा को 'माफ करो और भूल जाओ' की सलाह देकर इतने संगीन मुद्दे को टाल दिया। आहत-अपमानित स्वाभिमानी महिला (तरुणा) के लिए आखिरी दम तक लड़ने के सिवा रास्ता ही क्या रहा? तरुणा ने दिल्ली पहुंचकर अपना जेहाद तेज कर दिया। अखबारों ने कांग्रेसियों की करतूतों को जगजाहिर कर दिया। देशभर में थू-थू हुई और टोकस को पद से हटना पड़ा।

किस्सा-दर-किस्सा: जायकेदार किस्से और भी हैं। इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अपना उद्घाटन भाषण (लिखित) पढ़ते हुए कोरियाई राष्ट्रपति का नाम 'किमिल सुंग' के बजाय 'किल डाग' कह दिया। कोरियाई प्रतिनिधियों ने तुरंत टोका, "हमारा राष्ट्रपति डाग (कुत्ता) नहीं है, जनाब!" लेकिन आजाद ने क्षमा मांगने की हया तक नहीं दिखायी। कांग्रेस प्रतिनिधि अपने सूटकेसों में भारतीय शराब की बोतलें भर कर ले गये थे। उन्होंने जबरन विदेशी प्रतिनिधियों के गले में शराब उड़ेल दी, "भारत से यही भेंट हम आपके लिए ले आये हैं।" यही नहीं, कोरिया में इन कांग्रेसी युवकों ने रूसी विमान-परिचारिकाओं और विदेशी महिला प्रतिनिधियों के माथे पर बिंदी चिपकाकर दावा किया, "अब तुम्हारी शादी हो गयी।" विमान में वे पूरी आवारगी के साथ गाते रहे, "मेरा जूता है जापानी, यह पतलून इंगलिश्तानी...।"

एक रात कुछेक कांग्रेसियों ने तेलुगूदेशम प्रतिनिधि को आननफानन धर दबोचा। बहाना यह था कि उसने उनकी 'आपत्तिजनक स्थिति' की तस्वीर खींच ली है। कहा जाता है कि इन तमाम बदतमीजियों का अगुवा बहमा यादव नामक कांग्रेसी युवक था। आरोप है कि मुख्य घपलेबाजों में गिना जानेवाला यह युवक कुछ लड़कियों को संदेहास्पद जगहों पर ले जाता था। कांग्रेसी प्रतिनिधियों की भीड़ में एक लड़की को 'पामेला बोर्डेस' कहा जाता था। वही आकर्षण का केंद्र बनी थी। मजा यह कि ये अभद्रताएं 'राजीव-इंदिरा जिंदाबाद' के नारे के साथ की गयीं। जनता दल के प्रतिनिधियों ने समारोह में जब इन हरकतों पर विरोध जताया, तो कांग्रेसी लड़ने पर आमादा हो गये। कोरिया में सांस्कृतिक मंच पर कांग्रेसी और जद प्रतिनिधियों में हाथापायी भी हुई।

पीड़ितों का आरोप: बहरहाल, प्योंगयांग प्रकरण अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि १५० बददिमाग कांग्रेसी युवकों का जमावड़ा जुट जाने के बाद पार्टी की संस्कृति का पुरजोर प्रदर्शन स्वाभाविक था। उनके लिए राजनीति एक खेल है, अधिक-से-अधिक लाभ पाने का जुगाड़ है। यह उन्होंने अपने नेताओं से ही सीखा है। २५ साल से ऊपर के ऐसे पढ़े-लिखे कार्यकर्ता युवक कांग्रेस के 'ग्रीन हीरो' कहलाते हैं। नेतृत्व देश-विदेश के समारोहों में इन्हें ही सारी सुविधाएं देकर भेजता है, क्योंकि इनके साथ तमाम गिरोहों की जनशक्ति है। फिर यह बात, कम-से-कम सत्तारूढ़ दल के लिए, गौण हो जाती है कि ये शर्मिंदगी लेकर वापस आते हैं और घपलों-घोटालों की शान विदेशों तक पहुंचा आते हैं। ये गंदी हरकतें युवक कांग्रेस की सांस्कृतिक विरासत है। १९८३ के नागपुर वार्षिक सम्मेलन में, १९८५ के मास्को विश्व युवा समारोह में और अप्रैल, १९८२ में दिल्ली में आयोजित युवक कांग्रेस समारोह में भी यही सब हुआ, जिसे याद कर आज भी लोगों को शर्म का अहसास होता है।

पीड़ित प्रतिनिधियों का कहना है कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक, बारंबार दुहराई जानेवाली इन हरकतों से स्पष्ट है कि या तो राजीव गांधी अपने इन युवा साथियों पर, जिन पर ५ करोड़ नये मतदाताओं को तैयार करने के लिए वे (राजीव) भरोसा किये बैठे हैं, नियंत्रण रखने में अक्षम हैं या ऐसी गंदी हरकतों को अपनी मंजूरी दे चुके हैं।

—राजन गुहा

मैंने अपना दायित्व निभाया है : त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी

छाया : एस पाल

बोफोर्स पर सीएजी रिपोर्ट

विपक्ष का ब्रह्मास्त्र ?

कांग्रेस का जवाबी हमला

चुनावी दृष्टि से पिछले तीन महीनों से कांग्रेस की स्थिति सुधार पर थी और राजीव गांधी आक्रामक मुद्रा में थे, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने फिर से बोफोर्स के मुद्दे को जिंदा करके विपक्ष के हमले में जान डाल दी है। वाम और दक्षिण का भेद भुलाकर एक साथ लोकसभा से इस्तीफा देनेवाला विपक्ष आज अभूतपूर्व आक्रामक मुद्रा में है। दूसरी ओर कांग्रेसी सांसद राव वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा देकर और कर्नाटक के एचएन नानजे गौडा ने प्रधानमंत्री को कड़ा पत्र लिखकर बगावत की शुरुआत कर दी है। चुनाव युद्ध में कांग्रेस को मात देने के लिए विपक्ष इस सीएजी रिपोर्ट को ब्रह्मास्त्र मानकर चल रहा है। क्या वास्तव में विपक्ष इस रिपोर्ट को चुनाव में ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर पायेगा ? इस अप्रत्याशित राजनीतिक संकट से उबरने के लिए कांग्रेस की जवाबी रणनीति क्या है ?

अब जनता की अदालत में : इस्तीफा देकर लोकसभा से बाहर आते विपक्षी सांसद

छाया : एम पाल

दृश्य एक : संसद के वर्षाकालीन सत्र का तीसरा दिन—बृहस्पतिवार १९ जुलाई, १९८९। लोकसभा में शून्यकाल आरंभ होते ही विपक्ष के लगभग ५० सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर खड़े हो बोफोर्स तोप घोटाले पर सीएजी (महालेखा परीक्षक) द्वारा भारत सरकार को दोषी ठहराये जाने पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें सदन में बुलाने और 'राजीव गांधी चोर हैं' की सामूहिक गगनभेदी नारेबाजी। 'वीपी सिंह चोर हैं' के जवाबी नारे लगाती उत्तेजक कांग्रेसी प्रतिक्रिया। संसदीय मामलों के मंत्री हरिकिशनलाल भगत की अपनी पार्टी के सांसदों को आपे से बाहर हो जाने से रोकने की लगातार कोशिश। इस समूची आपाधापी में लाचार लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ द्वारा एक दिन में सात बार सदन की बैठक स्थगित करने का नया रिकार्ड। यही दृश्य लगातार तीन दिनों तक संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होता रहा। गौरतलब है कि इस अभूतपूर्व, अशोभनीय और संगीन प्रकरण के तीनों दिन सदन के नेता प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुछ ही गज दूर स्थित संसद के अपने कक्ष में मौजूद रह काफी की चुस्कियों के बीच समस्त गहमागहमी का जायजा तो लेते रहे, किंतु इस दौरान उन्होंने एक बार भी सदन में उपस्थित हो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देना तो दूर स्थिति पर नियंत्रण करने का भी कोई प्रयास नहीं किया।

दृश्य दो : सोमवार, २४ जुलाई। प्रश्नकाल आरंभ होते ही तेलुगू देशम के ही के सी माधव रेड्डी का आगे बढ़कर लोकसभा से विपक्ष द्वारा ५० वर्ष के इतिहास में पहली बार इस्तीफा देने का श्रीगणेश। उसके अगले १२ मिनट तक पंक्तिबद्ध ७२ अन्य विपक्षी सदस्यों का एक-के बाद-एक अध्यक्ष को इस्तीफा देते रहना। इस्तीफा देनेवालों में १२ विपक्षी दलों के एक-से-एक दिग्गज नेता थे। मसलन—जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह, माकपा के सोमनाथ चटर्जी, भाकपा के इंद्रजीत गुप्त, कांग्रेस-स के केपी उन्नीकृष्णन, जनता दल के मधु दंडवते, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां, भाजपा के एके पटेल, अकाली दल के चरनजीत सिंह अटवाल, फारवर्ड ब्लाक के अमर राय प्रधान, आरएसपी के पीयूष तिड़के, पीडब्ल्यूपी के डीबी पाटिल, द्रमुक के डा० करुणानिधि आदि। पिछले तीन दिनों के हंगामी माहौल में गैरहाजिरी के बाद उस दिन सदन में मौजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विपक्ष के सामूहिक इस्तीफे की बाढ़ में मनःस्थिति क्या थी, यह तो कहना कठिन है, किंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चेहरा भावविहीन रहा। विपक्ष को ऐसा कठोर कदम उठाने से रोकना तो दरकिनार उन्होंने न तो उसकी भर्त्सना की, न ही खेद प्रकट किया।

दृश्य तीन : २५ जुलाई। राज्यसभा में कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य चिमनभाई मेहता द्वारा सरकार के प्रति अपनाये गये आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के ही डीपी राय ने इस वरिष्ठ सदन की छत और प्रधानमंत्री की नाक तले उनका (मेहता का) गला पकड़ लिया और हाथापाई होते-होते बची। राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेता पी शिवशंकर और संसदीय कार्य राज्यमंत्री एमएम जैकब ने हादसे को हद से बाहर जाने से रोकने का कार्य अवश्य किया, किंतु प्रधानमंत्री अपनी चिरपरिचित तटस्थ, जड़वत मुद्रा में बैठे रहे।

संसद में घटित इन तीनों दृश्यों के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने दो ही निष्कर्ष निकाले हैं। एक, प्रचंड बहुमत के मंद में चूर प्रधानमंत्री अपने दायित्व के प्रति या तो अनभिज्ञ हैं या लापरवाह। दूसरे, इस दूरगामी अभूतपूर्व राजनीतिक संकट ने उन्हें किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है।

घटना ही इस प्रकार की थी कि प्रधानमंत्री का हतप्रभ और किंकर्तव्यविमूढ़ रह जाना आश्चर्यजनक नहीं था। कारण, पांच दशक से अधिक पुराने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार संपूर्ण विपक्ष ने अप्रत्याशित रूप से सामूहिक इस्तीफे दे लोकसभा को 'कांग्रेस सभा' में परिवर्तित कर दिया था। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कोई नया दस्तावेजं नहीं था। पिछले दो वर्षों से विपक्ष बोफोर्स तोप के गोले लगातार सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री को लक्ष्य बनाकर दागता रहा है। सीएजी की तैयार रिपोर्ट भी गत अप्रैल से सरकार के पास थी। उसके एक-एक शब्द से परिचित सरकार का संभावित विपक्षी हंगामे की अपेक्षा न करना आश्चर्यजनक बात थी। संसद में विपक्ष के सुनियोजित हमले का सत्तापक्ष किस तदर्थवाद के तहत मुकाबला कर रहा था, यह दो बातों से उजागर है। एक, सदन में प्रबंध कौशल का पूर्ण अभाव था। दूसरा, वरिष्ठ नेता व मत्री गैर मौजूद थे।

कदाचित कांग्रेस को इस बात का कतई अहसास नहीं था कि समूचा विपक्ष अभूतपूर्व ढंग से वाम और दक्षिण के भेदभाव मिटाकर सामूहिक इस्तीफे की हद तक पहुंच जायेगा। वह तो समझती थी कि थोड़ी बहुत झंझट होगी, इस कारण वह चिंतित नहीं थी। कांग्रेस को यह विश्वास था कि जिस प्रकार जैल सिंह बनाम राजीव गांधी प्रकरण और गत राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वामपंथियों ने अलग जाकर विपक्षी मंसूबों पर पानी फेर दिया था, उसी प्रकार इस बार भी वह विपक्ष से अलग रहेगा। नतीजतन वामपथी दलों की शेष विपक्ष से एकजुटता ने कांग्रेस को सकते में डाल दिया।

एकता तोड़ने की कोशिश : विपक्षी एकजुटता की भनक मिलते ही कांग्रेस ने इसे रोकने-तोड़ने की भरपूर कोशिश की। विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि भाकपा को मनाने-पटाने का प्रथम प्रयास कांग्रेस के महासचिव (पूर्व कम्युनिस्ट) केदारनाथ सिंह ने किया। मुंहतोड़ जवाब मिला कि कांग्रेस ने वायदा-खिलाफी की है, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है और जनविरोधी नीतियां बरकरार रखी हैं। हिम्मत कांग्रेस ने तब भी नहीं हारी। प्रयास का बीड़ा रविवार को गृहमंत्री बूटा सिंह ने उठाया। भोर में नैनीताल से और दोपहर तथा शाम को दिल्ली से टेलीफोन पर वरिष्ठ भाकपा नेताओं को मनाने का अथक प्रयास हुआ, किंतु दोटूक जवाब मिला कि तीर कमान से निकल चुका है।

माकपा को लेकर भी कुछ कम प्रयास नहीं हुए, किंतु मास्को में इलाज करा रहे पोलित ब्यूरो सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत की गैरमौजूदगी आड़े आयी। जानकार सूत्रों का दावा है कि महासचिव नंबूदिरीपाद अकेले पड़ गये थे और कलकत्ते का प्रबल ज्योति बसु कैंप नौजवान नेताओं के आग्रह पर विपक्षी एकजुटता के लिए मन बना चुका था। ज्योति बसु के पास अंतिम क्षण तक दूत भेजा गया, किंतु कामयाबी हाथ न लगी, क्योंकि बसु गत विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री की कड़ी टिप्पणियों से पहले ही खार खाये बैठे थे। शीला दीक्षित की हाल की मानमनौव्वल से कुछ नर्म पड़े मार्क्सवादी मुख्यमंत्री उस बातचीत के दौरान केंद्र द्वारा किये गये चंद वायदों पर अमल न किये जाने से भी बुरी तरह बिफरे हुए थे। रही-सही कसर शासक दल के राज्यों के अधिकारों में कटौती के एक-के-बाद एक लाये जानेवाले विधेयकों ने पूरी कर दी। अतः माकपा भी राजीव सरकार के खिलाफ एकजुट मुहिम में शामिल होने के लिए मजबूर थी।

इस एकजुटता के बाद भी कांग्रेस को इस बात की आशंका नहीं थी कि विपक्ष सामूहिक इस्तीफे का मार्ग अपनायेगा। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के मामले जैसी विपक्षी सदस्यों के सामूहिक निष्कासन की नौबत न आये, वह तो सिर्फ इस हद तक ही चौकन्नी

ऐतिहासिक फैसला : इस्तीफे की रणनीति को अंतिम रूप देते हुए आंध्र भवन में विपक्षी नेता

छाया : एम पाल

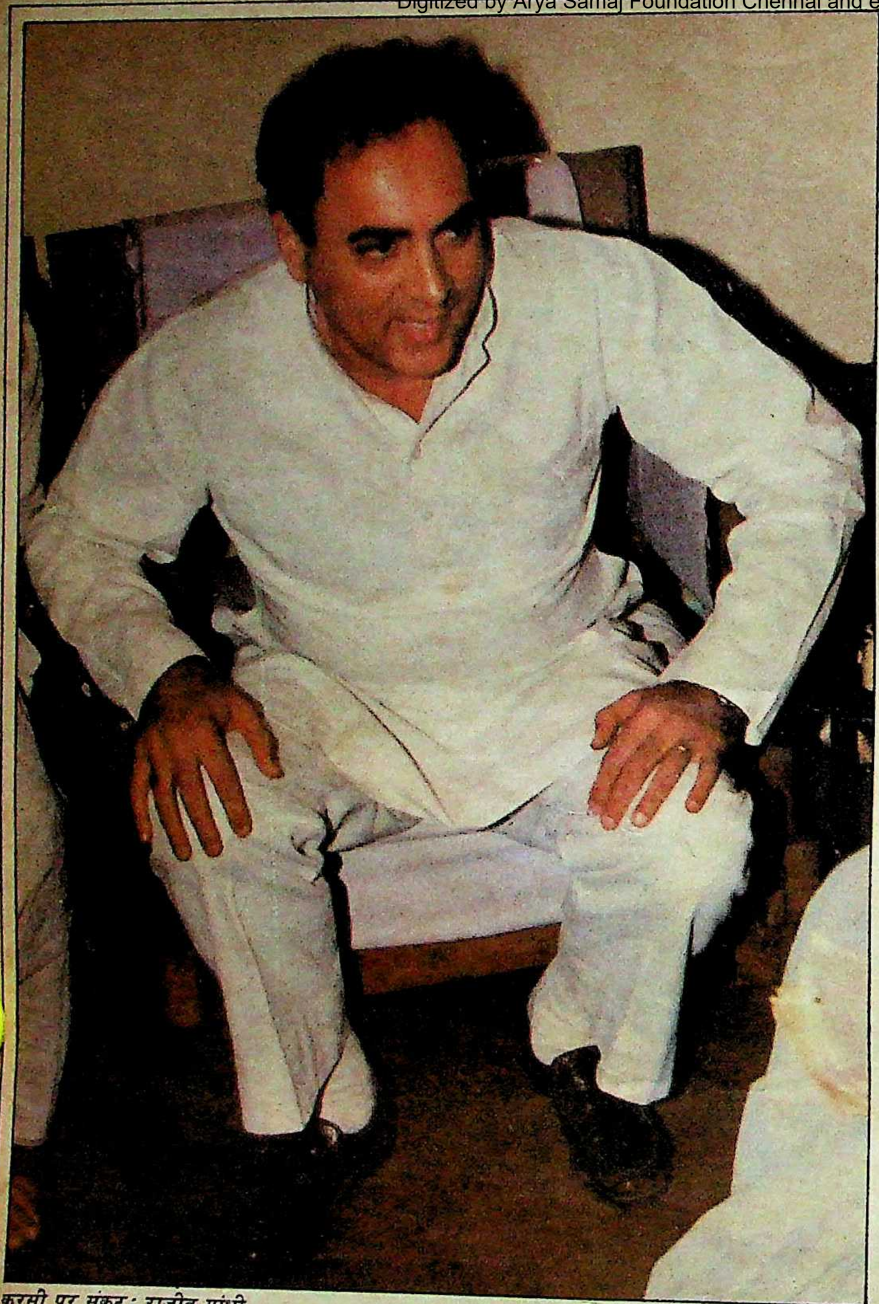

कुरसी पर संकट : राजीव गांधी

छाया : दीपक कुमार

थी। पार्टी के जुझारू सदस्यों ममता बनर्जी, शाताराम नाइक, विलास बाबूराव मुत्तमवार आदि को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि विपक्ष चाहे कितनी भी उत्तेजना पैदा क्यों न करे उन्हें मर्यादा का उल्लंघन कर विपक्ष को कोई मौका नहीं देना है। उसे गुमान तक नहीं था कि विपक्षी सांसद, संसद सदस्य बने रहने पर मिलनेवाले डेढ़ हजार मासिक वेतन और तीन हजार रुपए मासिक निर्वाचन भत्ते, निःशुल्क आवास, टेलीफोन तथा रेल व हवाई यात्रा की सुविधा का चुनाव वर्ष में इतनी आसानी से मोहत्याग देंगे।

समस्त सतर्कता के बावजूद विपक्ष ने आम राय तुरतफुरत कल ५२ घंटे में बनायी थी। पहल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने की। शुक्रवार को तड़के उन्होंने भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु को फोन करके यह पेशकश की कि सीएजी रिपोर्ट के मुद्दे पर लोकसभा के विपक्षी सदस्यों को इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पार्टी के अपने नेताओं से बातचीत करने का वायदा किया। वीपी सिंह भी बिहार के दौरे से वापस आ गये। एनटीआर के अलावा अन्य विपक्षी मुख्यमंत्री ज्योति बसु, देवीलाल, प्रफुल्ल महंत भी चटपट दिल्ली पहुंच गये और विचार-विमर्श के बाद आम सहमति बन गयी।

विपक्ष की रणनीति : दिलचस्प तथ्य यह है कि उनकी मांग पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस्तीफा देंगे, इसका किंचितमात्र विश्वास विपक्ष को कभी नहीं था। दूसरे, सीएजी रिपोर्ट पर बहस की अप्रत्याशित मांग भी विपक्ष ने ही उठायी थी। परंपरानुसार सीएजी रिपोर्ट पर सदन में कभी बहस नहीं होती। उसे आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को सौंप दिया जाता है। मात्र एक बार पूर्व रक्षामंत्री कृष्ण मेनन के कार्यकाल में जीप घोटाले से संबंधित सीएजी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा हुई थी, वह भी ऐन रिपोर्ट पर नहीं, उसके प्रकाशित अंशों को लेकर। प्रश्न उठता है कि विपक्ष ने पहले रिपोर्ट पेश होते ही यह अप्रत्याशित मांग क्यों रखी और बाद में इसी मुद्दे पर सामूहिक इस्तीफा दे, कांग्रेस द्वारा भगोड़ा करार दिये जाने का मौका क्यों दिया?

इस संबंध में प्रस्ताव पेश करनेवाले वरिष्ठ जनता दल सांसद मधु दंडवते ने 'माया' से विशेष भेंट में बताया, "१८ जुलाई ५ बजे शाम को सीएजी रिपोर्ट पेश होने के तुरंत बात मैंने धारा-१९३ के तहत नोटिस दे दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि रिपोर्ट ने सरकार की कलई अवश्य खोली होगी। हम उसे हरहाल देश के सम्मुख उजागर करना चाहते थे। हमें यह भी आशंका थी कि यदि रिपोर्ट को बहस के बिना पीएसी में भेजा जायेगा, तो विपक्षविहीन पीएसी उसमें लीपापोती कर सरकार को बरी कर देगी।"

विपक्ष के बहस में भाग न लेने के संबंध में दंडवते ने बताया, "उनके नोटिस देने के तुरंत बाद ही संयुक्त संसदीय समिति के पूर्व सदस्यों ने एक बयान जारी कर सीएजी पर दुराग्रहपूर्ण विकृति और पक्षपात का आरोप लगा हल्ला बोल दिया। इतना ही नहीं स्वयं रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर सीएजी को चुनौती दे डाली। नतीजतन, विपक्ष ने विचार-विमर्श से फैसला कर अध्यक्ष को सूचित किया कि हम बहस में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमें संदेह है कि इसके (बहस के) बहाने शासक दल नियत्रक और लोक लेखा परीक्षक पर व्यक्तिगत और संस्थागत आक्रमण कर उसकी अवमानना करेगा। राज्यसभा में एनकेपी साल्वे के रवैये और महालेखा परीक्षक त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी के संबंध में अभद्र भाषा के उपयोग ने हमारे इन संदेहों की पुष्टि की है।"

मार्क्सवादी सांसद सैफुद्दीन चौधरी ने जोड़ा, "बहस के लिए शेष ही क्या रहा था? पिछले दो वर्षों से सांसद के भीतर-बाहर व्यापक धुआंधार बहस चली थी। सीएजी के सम्मुख भी सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भरपूर मौका रहा है। अतः सरकार के बहस कराने के अड़ियल रुख के पीछे मकसद सीएजी पर कीचड़ उछालना था। हम सदन के भीतर एक संवैधानिक संस्था का हनन करने के

के एन सिंह

विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि भाकपा को मनाने-पटाने का प्रथम प्रयास कांग्रेस के महासचिव (पूर्व कम्युनिस्ट) केदारनाथ सिंह ने किया। मुंहतोड़ जवाब मिला कि कांग्रेस ने वायदा-खिलाफी की है, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है और जनविरोधी नीतियां बरकरार रखी हैं।

केसी पंत

साल्वे ने तो रिपोर्ट को ताक पर रख सीएजी को यह कह निशाना बना लिया कि उसने अपने अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत ने जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधों पर डालकर सरकार के बचाव का मार्ग ढूंढा।

सरकारी षड्यंत्र में भागीदार कैसे होते?"

जवाब में कांग्रेस सांसद नरेश चंद्र चतुर्वेदी बोले, "जब विपक्ष ने स्वयं सीएजी रिपोर्ट पर बहस का नोटिस दिया था, तो बाद में उससे यह कहकर क्यों भागे कि यह परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध है, और वह बहस नहीं चाहते। मैं तो इसे विपक्ष की असफलता और कुंठा का प्रतीक मानता हूं। विपक्ष के भागने के पीछे यह स्पष्ट कारण रहा कि इसमें जिम्मेदारी सीधे-सीधे वीपी सिंह पर जाती, जिन्होंने वित्तमंत्री के रूप में संपूर्ण सौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसे में, वह प्रधानमंत्री पर झूठी तोहमत लगा उन्हें बदनाम नहीं कर पाते।"

सीएजी रिपोर्ट पर बहस की मांग करने के बावजूद विपक्ष इससे पीछे हटा, तो कांग्रेस को भी यह मांग स्वीकार करने पर अफसोस हुआ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार गत २८ जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया कि बहस की मांग को स्वीकार कर और बाद में उस पर अड़कर हमने गलती की। एक, तो इससे परंपरा भंग हुई। दूसरे, विपक्ष को इस पर सामूहिक इस्तीफा देने का मौका मिल गया।

विभिन्न विकल्प: प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष में कुछ मतभेद रहे। विपक्ष के एक सांसद के अनुसार, "तेजी से बदलते घटनाक्रम के चलते एनटी रामाराव ने हमें एक ऐसी अंधी गली में पहुंचा दिया, जहां इस्तीफे के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।" उक्त सूत्र ने बताया कि एक अन्य सुझाव पहले यह भी था कि बहस में भाग लेकर सरकार की मिट्टीपलीत की जाये। फिर, प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के विरुद्ध सदन में गलतबयानी करने और उसे गुमराह करने के आरोप में विशेषाधिकार प्रस्ताव द्वारा उनकी छीछालेदर की जाये। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर सामूहिक इस्तीफा दे, भरपूर राष्ट्रव्यापी राजनीतिक लाभ उठाया जाये, किंतु अंततोगत्वा रामाराव की इच्छा सर्वमान्य रही। और विपक्ष ने बहस में भाग न लेने के फैसले के कारण सोमवार को सबसे पहले सामूहिक इस्तीफे पेश कर दिये। यदि इस्तीफे पेश न होते, तो उस दिन बहस में भाग लेना उनकी मजबूरी हो जाती, क्योंकि कांग्रेस की ममता बैनर्जी के प्रस्ताव पर यह विषय बहस के लिए उस दिन की कार्यवाही के एजेंडे में शामिल था।

विकल्प के बारे में विपक्ष ने ही नहीं शासक दल ने भी सोचा-समझा था। गत २२ जुलाई को राजधानी के सत्ता गलियारों में एक ओर यदि विपक्ष के सामूहिक इस्तीफे की चर्चा गर्मा रही थी, तो दूसरी ओर लोकसभा भंग होने की खबर भी। इस अफवाह को फैलाने का काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हुई एक घंटे की मुलाकात ने भी किया।

'माया' को एक जानकार सूत्र ने बताया कि उस शाम हरकिशनलाल भगत के निवास पर एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें गृहमंत्री बूटा सिंह, शीला दीक्षित, पी शिवशंकर आदि मौजूद थे। बैठक में आसन्न राजनीतिक संकट से उबरने पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। विपक्ष की नाटकीय पहल के पूर्व बाजी अपने हक में करने के लिए लोकसभा भंग करने पर लगभग आम सहमति बन गयी थी, किंतु अंत में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकारों ने इस पर अमल न करने की राय दी। उनकी राय थी कि इस समय लोकसभा भंग करके चुनाव मैदान में जाने का अर्थ होगा विपक्ष द्वारा चुने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, जिसमें लेने-के-देने पड़ सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बूटा सिंह, सतीश शर्मा और आरके धवन की विशिष्ट सलाहकार तिकड़ी ने प्रधानमंत्री को समझाया कि वर्तमान भंडाफोड़ (सीएजी रिपोर्ट) और चुनाव के बीच अंतराल होने पर ही पार्टी लाभ की अपेक्षा भी कर सकती है और अपने मनमाफिक मुद्दे पर चुनाव मैदान में भी उतर सकती है।

कांग्रेस का पश्चाताप: ऐन चुनाव पूर्व हुए भंडाफोड़ से कांग्रेसी खेमे में हताशा और निराशा गहरायी है। अधिकांश कांग्रेसियों का मानना है कि रिपोर्ट को पिछले सत्र में पेश न करके बहुत बड़ी गलती की गयी है। यदि तब रिपोर्ट पेश हो जाती, तो अब तक विपक्षी गुबार थम चुका होता। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट सरकार को अप्रैल माह में मिल गयी थी। यद्यपि आधिकारिक सूत्र उसे पेश न किये जाने का कारण इस पर आवश्यक कार्रवाई और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न होना बताते हैं, किंतु जानकार सूत्र इसके पीछे दो मुख्य कारण बताते हैं। एक, तो सीएजी को फुसलाने-बहलाने-धमकाने के हथकंडों से उसे बदलवाने की इच्छा और प्रयास। दूसरे, इस दौरान इस बात का अथक प्रयास कि बोफोर्स से कथित दलाली के वे ६४ करोड़ रुपए हासिल कर सरकार पर टिकी संदेह की सुई को हटाया जा सके, जिसका सुझाव तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह जाते-जाते दे गये थे। किंतु दोनों ही प्रयास विफल रहे। क्योंकि सीएजी ने कड़ा रुख अपना लिया और बोफोर्स को अपनी फजीहत का भय था।

पिछले सत्र में रिपोर्ट पेश न करने की यदि गलती की गयी थी, तो इस सत्र के पहले ही दिन उसे पेश करने की भारी भूल-चूक का दोष भी अनेक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के सलाहकारों के सिरमाथे मढ़ रहे हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 'माया' से बातचीत में कहा, "यदि यही रिपोर्ट हमने पंचायत विधेयक आदि पारित करने के बाद प्रस्तुत की होती, तो न तो

लुंजपुंज विपक्ष एकजुट हो पाता और न इतना हंगामा खड़ा करता। वह आपसी सिरफुटौवल में ही रत रहता।"

कदाचित, पूर्वमंत्री महोदय पार्टी नेतृत्व की विवशताओं से अनभिज्ञ थे। 'माया' को पड़ताल से पता चला है कि पहले ही दिन रिपोर्ट पेश करने का जोखिम उठाने के पीछे सरकार के पास यह सूचना थी कि रिपोर्ट प्रेस के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में उसे पेश करने में किसी प्रकार की टालमटोल का वही हश्र होता, जैसाकि ठक्कर आयोग रिपोर्ट का हुआ था। ज्ञात रहे कि ठक्कर रिपोर्ट के प्रेस में छप जाने के बाद सरकार उसे संसद में पेश करने को बाध्य हुई थी। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे जल्द से जल्द पेश करने की संवैधानिक विवशता भी थी।

रिपोर्ट पेश करने की विवशता चाहे जो भी रही हो, और कांग्रेस नेता साल्वे ने उसे 'रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य' क्यों न करार दिया हो, किंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि इसने कल तक तीन-तेरह विपक्ष को एकजुट करने का चमत्कारिक काम किया। हाल की कांग्रेसी सक्रियता और चुनावी योजनाओं द्वारा मतदाताओं को दिनदहाड़े दी जा रही रिश्वत के चलते पस्त पड़े विपक्ष को ताजा दम कर बाजी उसके हक में करने का श्रेय भी इसी रिपोर्ट को जाता है।

बूटा सिंह

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बूटा सिंह, सतीश शर्मा और आरके धवन की विशिष्ट सलाहकार तिकड़ी ने प्रधानमंत्री को समझाया कि वर्तमान भंडाफोड़ (सीएजी रिपोर्ट) और चुनाव के बीच अंतराल होने पर ही पार्टी लाभ की अपेक्षा भी कर सकती है।

गौरतलब है कि बोफोर्स और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पृष्ठभूमि में चला गया था, वह एक बार फिर पूरे जोरशोर से जनता-जनार्दन के मध्य पहुंच गया है। दूसरे, इसी रिपोर्ट को आधार बना विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर प्रकारांतर से उनको बोफोर्स घोटाले से सीधे-सीधे जोड़कर उनकी विश्वसनीयता पर पहले से लगे प्रश्नचिह्न को और गहराया है। यही नहीं, उनके (प्रधानमंत्री के) इस्तीफा न देने पर अपने इस्तीफे पेश कर विपक्ष ने स्वयं तो नैतिकता का बाना ओढ़ लिया और अप्रत्यक्ष रूप से राजीव गांधी को बेशर्म और अनैतिक घोषित कर दिया।

प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष कांग्रेस से हथियायी इस पहल को मतदान के समय तक बरकरार रखेगा अथवा जैसाकि कांग्रेस को उम्मीद है, उसके (विपक्ष के) रथ के विभिन्न पहिये कुरुक्षेत्र में पहुंचने के पूर्व ही धुरी से अलग हो विभिन्न दिशाओं में लुढ़क जायेंगे?

विपक्ष की योजनाएं: विपक्ष अपनी भावी संभावनाओं के प्रति पूर्णतया आश्वस्त और जागरूक प्रतीत होता है। अभियान के मार्ग पर पहले से ही अग्रसर विपक्ष ने इस मुद्दे को भी जनता की अदालत में ले जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और कांग्रेसी कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने का फैसला किया है। इसके चलते लोकसभा से इस्तीफा देनेवाले

साक्षात्कार: **त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी** (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक)

'जो भी रिपोर्ट पढ़ेगा, स्थिति स्वतः उजागर हो जायेगी'

माया: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (निमप) की भूमिका और कार्यक्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है?

चतुर्वेदी: निमप की भूमिका का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। १९७१ में इसको कुछ अन्य नियम-कानूनों से लैस किया गया। निमप की रिपोर्ट संविधान के अंतर्गत एक प्रशासनिक रिपोर्ट होती है। यह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों को अपने प्रशासनिक दायित्व निभाने में सहायता करती है। इसीलिए जो मेरी रिपोर्ट होती है, उसमें प्रशासनिक मुद्दे होते हैं। मसलन, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कोई कमी नजर आती हो, जिससे कि पैसे का उपयोग अच्छी तरह नहीं हो सका हो और जो उद्देश्य प्राप्त करने थे, वे नहीं हो सके तो उन्हें हमारी रिपोर्ट उजागर करनी है। हम कार्यप्रणाली की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य या मंतव्य नहीं होता।

माया: रक्षामंत्री समेत अनेक कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि निमप ने बोफोर्स जांच में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और तोप के तकनीकी पहलू पर उसे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

हम सबने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। मेरे या मेरी संस्था के बारे में कुछ कहा जाये, यह मेरा दुर्भाग्य है।

चतुर्वेदी: मैं इस मुद्दे पर संसद में गत २२ जुलाई को हुई बहस के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह तो न्यायविद ही तय करेंगे कि अधिकारक्षेत्र का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। मैंने तो संविधान के अंतर्गत दायित्व निभाने का एक छोटा सा कार्य किया है।

माया: क्या अब तक की कोई रिपोर्ट अथवा मौजूदा रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित रही है?

चतुर्वेदी: जैसाकि मैंने पहले कहा है, हमारी रिपोर्ट का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार लाना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रशासन में जो खामियां हैं, वे सरकार अथवा प्रबंधक के सामने आ जायें। सरकार चाहे, तो उस पर कार्रवाई करे। इसीलिए निमप की रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं होती। वह या तो केंद्र की लोक लेखा समिति (लोलेस) के पास अथवा राज्य में चली जाती है। लोलेस की रिपोर्ट पर भी बहस नहीं होती, क्योंकि वह गैरराजनीतिक मसविदा होता है। निमप और लोलेस किसी पार्टी के आधार पर काम नहीं करती हैं।

सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे एक से ८ अगस्त तक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित करें। इसमें बोफोर्स तोप के मामले में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला पेश करते हुए जनता को बतायें कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में बोफोर्स तोपों की गुणवत्ता और गोलाबारूद की संदिग्ध आपूर्ति और कार्यकुशलता पर व्यक्त संदेह के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार, "भ्रष्टाचार के मुद्दे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का प्रश्न हो गया है।"

यह प्रश्न ऐसा है, जिससे प्रत्येक भारतीय को आंदोलित-प्रभावित किया जा सकता है। जनता दल ने इसे ही भुनाने के लिए 'देश बचाओ' का नारा दिया है। उल्लेखनीय है कि इसी मुद्दे पर राजीव गांधी १९८४ में प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ तो हुए ही, इस बार भी वे इस मुद्दे का भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने को तत्पर दिखायी देते हैं। पिछले कुछ महीनों से हर मंच से इसकी गुहार लगाने में उन्होंने कभी कोताही नही बरती। सीएजी रिपोर्ट में दर्ज रक्षा-सौदे संबंधी अनियमितताओं-घोटालों के संकेतों को आधार बना विपक्ष ने देश की सुरक्षा-अखंडता का मुद्दा उठा 'मियां की जूती, मियां के सर' कहावत चरितार्थ करने की योजना बनायी है।

जगन्नाथ मिश्र

> **मुंह खोला बिहार के दो नेताओं-सीताराम केसरी और जगन्नाथ मिश्र ने। पार्टी अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की चुनौती को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। उसे मात देने के लिए हमें सुनियोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए।**

इसके अतिरिक्त १० से २६ अगस्त तक जिला, ब्लाक, तहसील और नगर स्तर पर विपक्ष ने जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इन अवसरों पर बोफोर्स घोटाले की विभिन्न रिपोर्टों, राजीव सरकार की जनविरोधी नीतियों के साथ अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि की सूचना सभाओं-रैलियों में दी जायेंगी। अभियान की चरम परिणति ३० अगस्त को 'भारत बंद' के रूप में होगी। इसे सफल बनाने का कार्यभार समस्त विपक्षी दलों के सुपुर्द कर दिया गया है जो युद्ध स्तर पर तैयारी के लिए कटिबद्ध प्रतीत होते हैं।

बदला परिदृश्य: सामूहिक इस्तीफे से बदले राजनीतिक परिदृश्य के चलते विपक्षी खेमे में यदि हौसले बुलंद रहे हैं, तो कांग्रेसी खेमा शुरुआती दिनों में निराशा के घटाटोप से घिरा रहा है। उच्च नेतृत्व की चुप्पी से दिशानिर्देश और आश्वासन का पूर्ण अभाव रहा। 'माया' प्रतिनिधि ने जब इस्तीफा प्रकरण के तुरंत बाद राजधानी स्थित विभिन्न प्रदेश भवनों का दौरा किया, तो इसी निराशा, हताशा को आम कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में विद्यमान पाया। कांग्रेस के एक सांसद ने 'माया' से कहा, "आज पार्टी का कोई धनीधोरी (जिम्मेदारी संभालनेवाला) नहीं है। अभूतपूर्व संकट है। किंतु आज दस दिन बाद भी पार्टी के किसी भी मंच पर कोई भी बैठक नहीं हुई है। पार्टी के सर्वोच्च मंच-

माया: बोफोर्स जांच के दौरान किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष ने क्या आप पर दबाव डालने का प्रयास किया?

चतुर्वेदी: किसी के दबाव डालने का सवाल ही नहीं है। चाहे वह राजनीतिक दल हों या राजनीतिक व्यक्ति। हमारे विभाग की परंपरा रही है कि हम पूर्णतया तटस्थ व निष्पक्ष दृष्टि से इन सब कामों को देखते-परखते हैं।

माया: रिपोर्ट कब तैयार हुई? विपक्ष का आरोप है कि रिपोर्ट संसद के पिछले सत्र में पेश की जा सकती थी, किंतु सत्ता दल की मंशा उसमें परिवर्तन कराने की थी।

चतुर्वेदी: रिपोर्ट में स्वयं तारीखें दर्ज हैं। किस दिन वह तैयार हुई, कब सरकार को भेजी गयी, उस पर तिथिवार मेरे हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट देने के बाद मेरा दायित्व समाप्त हो जाता है। कोई क्या कहता है, इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता।

माया: क्या आपका कोई व्यक्तिगत पूर्वग्रह रिपोर्ट तैयार करते समय आड़े आया जैसाकि सत्तापक्ष आरोप लगा रहा है?

चतुर्वेदी: व्यक्तिगत पूर्वग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं है। मुझे पदग्रहण करते समय बिना किसी भेदभाव अथवा भय के दायित्व निभाने की जो शपथ दिलायी गयी थी, उसी के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। अपने ३४ वर्ष के सेवाकाल में मैंने कभी व्यक्तिगत संबंध के स्तर पर काम नहीं किया।

माया: जिन कागजातों और रेकार्डों के आधार पर आपने रिपोर्ट तैयार की, लगभग उन्हीं के आधार पर संयुक्त संसदीय समिति (संसंस) ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, किंतु दोनों में इतना अंतर क्यों है?

चतुर्वेदी: दोनों रिपोर्टों की तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे विभाग ने १९८६ से बोफोर्स तोपों पर काम शुरू किया था। हमने संसंस की रिपोर्ट से कोई तुलना नहीं की। उसका (संसंस) जिक्र हमारी रिपोर्ट में तभी आया जब सुरक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में हमको लिखा। इसलिए उसका उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक हो गया। रिपोर्ट में मैंने लिखा है कि संसंस के प्रति मेरा पूरा आदर है, किंतु संविधान के अनुसार कार्य करना मेरा दायित्व है।

माया: आपको इसी रिपोर्ट की जांच का दुबारा मौका मिले, तो क्या आपके निष्कर्ष वही होंगे?

चतुर्वेदी: यह हाइपोथेटिकल (अटकलबाजी) सवाल है जितने भी कागज मेरे सम्मुख आये, उनके आधार पर जो निर्णय मैंने लिये हैं, मेरे हिसाब से वे उचित और समीचीन हैं। उससे हटने का कोई सवाल नहीं है।

माया: जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो क्या आपने सोचा था कि इससे इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा होगा?

चतुर्वेदी: मेरा तो राजनीतिक दृष्टि से सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो पहले से ही इस बारे में सतर्क थे, क्योंकि कुछ विवाद चल रहा था। इसलिए चाहे भाषा हो या तथ्य, मैं और मेरे अफसर अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण सजग थे। हम सबने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। मेरे या मेरी संस्था के बारे में कुछ कहा जाये, यह मेरा दुर्भाग्य है। हमारे अनुभवी अधिकारियों ने तथ्यों की रोशनी में पक्षपात रहित होकर काम करनें की कोशिश की है। अगर रिपोर्ट के बारे में कोई भ्रांति फैलती है, तो यह मेरा दुर्भाग्य है। जो भी रिपोर्ट पढ़ेगा, स्थिति स्वतः उजागर हो जायेगी।

माया: समस्त विवाद में न सिर्फ आप आलोचना के पात्र बने हैं, बल्कि असद्र भाषा के भी, जिसके तहत आपको 'चार्ली' तक की उपाधि दे दी गयी।

चतुर्वेदी: मैं शिष्ट-संयमित भाषा में विश्वास रख उसी का प्रयोग करता हूं। वैसे मेरी शिक्षा-दीक्षा तो नगर निगम के स्कूल में हुई है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से मेरे समय में तो 'कामिक्स' भी प्रचलित व उपलब्ध नहीं थे। अतः मैं तो 'स्लैंग' (अभद्र पारिभाषिक) भाषा के अर्थ से भी अपरिचित हूं।

—रंजना कक्कड़

संसदीय बोर्ड अथवा संसदीय दल तक की बैठक बुला विचार-विमर्श करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। इस समय सवाल चिंता-बेफिक्री का नहीं। सवाल पार्टी सदस्यों को विश्वास में लेने, जानकारी देने और रणनीति तैयार करने का है। मुट्ठी भर लोगों के साथ बातचीत और सलाह करने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई मूल्य नहीं है। आज शाम को पार्टी कार्यकारिणी समिति की जो बैठक बुलायी भी गयी है, वह पुराने कार्यक्रम के तहत है और नगरपालिका विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए है।" उस दिन २७ जुलाई को हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक यद्यपि आयोजित तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर थी, किंतु चार घंटे चली बैठक का तीन चौथाई समय विपक्ष के सामूहिक इस्तीफे, उससे उत्पन्न संकट और निपटने की रणनीति की चर्चा पर ही बीता।

जानकार सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने उपस्थित सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि विपक्ष के इस नाटक को हमारी प्रबुद्ध जनता भलीभांति जानती-समझती है। इसका कोई प्रभाव आगामी चुनाव पर नहीं पड़नेवाला है। सरकार हमारी ही बनेगी। आश्चर्य की बात यह है कि कड़े सुरक्षा घेरे में आबद्ध प्रधानमंत्री जनमत से अनभिज्ञ भले रहे हों, किंतु बैठक में उपस्थित अन्य नेता भी वस्तुस्थिति की जानकारी देने से कन्नी काटते रहे। मुंह खोला बिहार के दो नेताओं—सीताराम केसरी और जगन्नाथ मिश्र ने। पार्टी अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की चुनौती को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। उसे मात देने के लिए हमें सुनियोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए।

जवाबी रणनीति: प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कांग्रेस जवाबी रणनीति को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। किंतु रूपरेखा निश्चित तौर से तैयार कर ली गयी है। भावी रणनीति की सबसे पहली झलक संसद में सीएजी रिपोर्ट पर बहस के दौरान देखने को मिली। रिपोर्ट में दर्ज अनियमितताओं की कोई राजनीतिक काट न होने के कारण कांग्रेस के पास मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। साल्वे ने तो रिपोर्ट को ताक पर रख सीएजी को यह कह निशाना बना लिया कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत ने जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधों पर डालकर सरकार के बचाव का मार्ग ढूंढ़ा।

मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की यही रणनीति संसद के बाहर भी चलाने की योजना है। उसके तहत रक्षा सौदे के घोटाले को तो पूर्णतया अनदेखा किया जायेगा और विपक्ष पर लोकतंत्र की हत्या की कोशिश और मतदाताओं से विश्वासघात का आरोप थोपा जायेगा। इस पर पश्चाताप करने और विपक्ष द्वारा 'देश बचाओ' अभियान की काट के

सीएजी आखिर है क्या ?

संविधान सभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) पद पर अपना मत व्यक्त करते हुए भारतीय संविधान के पितामह डा० बीआर अंबेदकर ने कहा था, "इस अधिकारी (महालेखा परीक्षक) का संभवत: संविधान में सर्वाधिक महत्व है। यह वह व्यक्ति है जो देखेगा कि संसद ने खर्चों के लिए जो स्वीकृति दी है, उसमें बढ़ोत्तरी न हो और न कोई अंतर आये। इस अधिकारी की सेवाएं न्यायपालिका से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं।"

कदाचित डा० अंबेदकर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए ही संविधान के अनुच्छेद-१४८ के तहत सीएजी को वह संवैधानिक महत्ता और अधिकार तो प्रदान किये ही गये जो सर्वोच्च न्यायालय, संसद और चुनाव आयोग को प्राप्त हैं, किंतु इस अर्थ में उसे सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग से अधिक विशिष्ट स्थान दिया गया कि महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के बाद कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। यह प्रावधान उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए ही किया गया है।

यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किन्तु महालेखा परीक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। एक प्रकार से देखा जाये, तो वह संसद की पूरक भूमिका का भी निर्वाह करता है। संसद का प्रमुख काम राष्ट्रीय कोष का संरक्षण है। उसके तहत सरकारी कोष का कोई भी धन लोकसभा की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं होता। लोकसभा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों अथवा सेवाकार्यों के लिए विशिष्ट धनराशि की स्वीकृति देती है। सीएजी का यह काम होता है कि वह देखे कि लोकसभा के निर्देशों का विधिवत पालन हो और किसी प्रकार की फिजूलखर्ची अथवा अनियमितता न बरती जाये। उसकी (सीएजी की) ब्रिटेन के महालेखा परीक्षक से अलग हैसियत है। ब्रिटेन में वह संसद का एक अधिकारी होता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ब्रिटेन के महालेखा परीक्षक को संसद द्वारा मांगी गयी किसी भी रिपोर्ट को सदन में रखना लाजिमी होता है। भारत में संसद उससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मंत्री के माध्यम से ही प्रश्न कर सकती है।

भारत में सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद को नहीं राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसे संसद में भेजता है। सदन में पेश होने पर उसे स्वत: लोकलेखा समिति (पीएसी) को अगली जाचं के लिए भेज दिया जाता है। परंपरानुसार सीएजी रिपोर्ट पर संसद में कभी बहस नहीं होती।

सीएजी रिपोर्ट मूलत: लेखा (आडिट) रिपोर्ट होती है जो सरकार द्वारा भेजे गये मसौदों के आधार पर तैयार की जाती है। सीएजी कोई निजी जांच नहीं करता। मात्र सरकार द्वारा भेजे गये दस्तावेजों, अधिकारपत्रों, आदेशों और पत्र व्यवहार के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पहले सीएजी संबंधित फाइलों पर प्रस्तुत अपने संदेहों, टिप्पणियों के विषय में सरकार को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी भरपूर मौका देता है।

महालेखा परीक्षक बनाम संसदीय समिति

बोफोर्स तोप सौदों के संबंध में उठे विभिन्न गंभीर आरोपों की जांच के लिए २६ जुलाई, १६८७ को गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने इस सौदे को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस सौदे का हर पहलू और भी गंभीर आरोपों को जन्म देता है। दोनों रिपोर्टों के कुछ महत्वपूर्ण अंश यहां प्रस्तुत हैं:

संयुक्त संसदीय समिति

० समिति इस बात से पूर्णतया संतुष्ट है कि बोफोर्स तोप के चुनाव के लिए अपनायी गयी कार्यविधि दुरुस्त और निष्पक्ष थी। विभिन्न तोपों का तकनीकी मूल्यांकन सही ढंग से और सावधानी पूर्वक किया गया था।

० बोफोर्स के पक्ष में पलड़ाभारी उसकी मारक क्षमता के कारण हुआ। इसकी प्राथमिकता को सितंबर, १६८५ में तब नया आयाम मिला जब यह समाचार प्राप्त हुए कि एक शत्रु देश को मिले सैन्य सहायता पैकेज में अग्निशसन राडार शामिल कर दिया गया है।

० बोफोर्स से मूल्य और ठेके की अन्य शर्तें तय करने की बातचीत में कोई दलाल शामिल नहीं था।

० बोफोर्स तोपें एक मंझोली लड़ाकू तोप की आवश्यक तकनीकी और कार्य संचालन संबंधी मापदंडों पर खरी उतरती हैं। समिति के सामने पेश सबूत स्पष्ट करते हैं कि करार का

लिए कांग्रेस देशव्यापी 'शर्म सप्ताह' आयोजित करेगी।

ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इस सप्ताह के दौरान कस्बों और शहरों में आम सभाएं होंगी, बुद्धिजीवियों की गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी, शर्म-रैलियां निकाली जायेंगी और जनता-जनार्दन को बताया जायेगा कि स्वाधीन भारत के इतिहास में विपक्ष की इस हरकत ने किस प्रकार एक काला पृष्ठ जोड़ा है। कांग्रेस महासचिव केदारनाथ सिंह ने 'माया' से एक भेंट में कहा, "हम जनता के बीच जाकर उन्हें बतायेंगे कि मात्र शहादत का सेहरा लगाने के लिए विपक्ष ने इस्तीफे का नाटक किया। बोफोर्स और भ्रष्टाचार का गाना तो दो वर्ष से गाया जा रहा था, तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। यदि सिद्धांत के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा दिया गया, तो राज्यसभा से क्यों नहीं?" सांसद तारिक अनवर ने जोड़ा, "इस्तीफे जनता की सहानुभूति हासिल करने का भोंडा राजनीतिक हथकंडा हैं। चुनाव मैदान में उतरने के लिए विपक्ष के पास कुछ अन्य था ही नहीं। हम जनता को बतायेंगे कि सीएजी ने पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के खिलाफ भी रिपोर्टें दी हैं। विपक्ष उन राज्य सरकारों से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करता?"

विपक्षी नेताओं के चरित्रहनन के हथियार भी सान पर चढ़ाये जा रहे हैं, ऐसा जानकार सूत्रों का कहना है। इनके अनुसार लगभग हर जाने-माने विपक्षी नेता और विपक्षी सरकार की फाइल खोली जा रही है और उनकी दूरबीनी जांच जोरशोर से चालू है। इसके चलते आगामी सप्ताहों में विपक्षी नेताओं की बखिया उधड़ना सुनिश्चित है। वैसे कांग्रेस यह आशा भी संजोये बैठी है कि वर्तमान विपक्षी एकजुटता अवसरवादी व चंदरोजा है। जब आपसी सिद्धांत-स्वार्थ टकरायेंगे, तो उसमें विभाजन अवश्यंभावी है। जब इसकी चर्चा जनता दल के राज्यसभा नेता एस गुरुपदस्वामी से चली, तो वे बोले, "देश बचाओ के मुद्दे पर सभी दल एक मत हैं। वाम और दक्षिण के भेदभाव आड़े न आयें, इसीलिए जनअभियान के लिए ही हमने संयुक्त कार्रवाई की जगह तालमेलयुक्त कार्रवाई का मार्ग अपनाया है।" कांग्रेस भी कुछ कम चौकन्नी नहीं। उसने विपक्ष के विभाजन की जो पुरानी मुहिम है, उसे न केवल बरकरार रखने, बल्कि गति देने का निश्चय किया है।

सकारात्मक कार्यक्रमों का विशिष्ट प्रभाव रहता है। यह जानते-समझते कांग्रेस पंचायत राज और जवाहर रोजगार योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी। ज्ञात रहे, इनकी बैसाखियों से ही कांग्रेस हाल में लोकप्रियता के नये आयाम तक पहुंची थी। वर्तमान सत्र में पंचायत राज विधेयक प्रस्तुत कर उसने विपक्ष को सांसत में

निर्णय पूर्णतया गुणों के आधार पर किया गया। इसके गोला बारूद को चुनने के लिए भरपूर अभ्यास भी किये गये। अंततः समझौता करनेवाली समिति ने फरवरी, १९८६ में तय किया कि बोफोर्स के अलावा दूसरे तोप निर्माताओं के पास गोला बारूद खरीदने जाना ठीक नहीं होगा।

- बोफोर्स से करार की एक खास वजह थी देश की रक्षा तैयारियों के संबंध में बोफोर्स तोप की गति।
- सरकार सबसे कम मूल्य और बेहतरीन शर्तों पर ठेका पाने में कामयाब रही।
- यह एक अत्याधुनिक तोप है जो अनेक वर्षों तक काम करेगी। उसकी खरीदारी पर ही नहीं, बल्कि बाद के चरण में लाइसेंसशुदा उत्पादन पर भी विचार किया गया।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक

- तोप और गोला-बारूद का तकनीकी मूल्यांकन खामियों से युक्त था। सामान्य (जनरल) स्टाफ की जरूरतें तैयार नहीं की गयी थीं। निर्माताओं द्वारा समय-समय पर किये दावों की पूरी तरह जांच-परख भी नहीं की गयी। सेना मुख्यालय ने दिसंबर, १९८२ से अक्तूबर, १९८५ के बीच एक नहीं छह विभिन्न अवसरों पर सोफमा (फ्रेंच) तोप प्रणाली की अपनी पसंद का इजहार किया था। बहरहाल, सेना मुख्यालय ने फरवरी, १९८६ में अपनी पसंद बदल दी और बोफोर्स की सिफारिश की। मार्च, १९८६ में बोफोर्स से करार पर हस्ताक्षर हुए।
- यह देखा गया कि बोफोर्स और सोफमा-दोनों सेना द्वारा गोला दागने संबंधी न्यूनतम स्वीकृत मापदंडों (१५ से २० सेकेंड में तीन राउंड) पर खरे उतरते थे। किंतु बोफोर्स के पक्ष में भेद का सीमांत २ सेकेंड था।
- प्रतिद्वंद्वी तोप निर्माता फ्रेंच फर्म सोफमा ने मई, १९८५ में मंत्रालय को लिखा था कि उसने अपने भारतीय एजेंट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। मंत्रालय ने ऐसा ही लिखित आश्वासन दूसरे बोलीदाता-बोफोर्स से लेना उचित नहीं समझा। जुलाई, १९८५ में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने मंत्रालय को सूचित किया कि बोफोर्स का भारत में एक प्रतिनिधि (एनाट्रानिक जनरल कार्पोरेशन, नयी दिल्ली) है। इस सूचना के बावजूद मई, १९८५ में निर्माताओं को भेजी गयी चेतावनी और अयोग्यता के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बोफोर्स से हुए करार में ऐसे किसी एजेंट को हटाये जाने का कोई-प्रावधान नहीं था।
- स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के अनुसार बोफोर्स और एक बेनामी पार्टी में तोप सौदे के कमीशन पर समझौता हुआ था और एक बड़ी रकम बोफोर्स के भारत स्थित पूर्व एजेंट सहित अन्य को अदा की गयी। स्वाभाविक है कि करार में एजेंटों की अलहदगी का प्रावधान न होने से मंत्रालय बोफोर्स से एजेंटों को दी गयी रकम के आधार पर मूल्य में कमी की मांग नहीं कर सकता था।
- सेना मुख्यालय के न्यूनतम स्वीकृत मापदंडों की उपेक्षा करने के बाद ३२८.९८ करोड़ के गोलाबारूद का आर्डर दिया गया। सेना मुख्यालय पहले गोलाबारूद के आर्डर को उसकी सीमित मारकक्षमता की बिना पर रद्द कर चुका था। किंतु उसका पुनः आर्डर दिया गया। दो मामलों में गोला बारूद डिपो अधिकारियों ने जब गोलाबारूद कनस्तरों को खोला, तो वे खाली थे। कनस्तरों को इसलिए खोला गया था, क्योंकि वे काफी हल्के थे। इस आकस्मिक जांच से संदिग्ध या कम आपूर्ति के अलावा यह भी सिद्ध हुआ कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि कनस्तर अमूमन इस्तेमाल के समय ही खोले जाते हैं।
- अक्तूबर, १९८८ तक चंद रेजिमेंटों को १५५ एमएम तोप प्रणाली से लैस करने की संभावना थी। किंतु उस दिन तक सेना द्वारा जारी साज-सामान से एक भी रेजिमेंट तोप प्रणाली से लैस नहीं हो सकी। यद्यपि आपूर्ति में चार सप्ताहों से अधिक की देरी हर्जाने की हकदार थी, किंतु जब लेखा (आडिट) ने संकेत किया कि गत वर्ष हर्जाना ८३.३० लाख तक पहुंच गया है, तभी मंत्रालय ने अंततः हर्जाने का दावा पेश किया।
- बोफोर्स को ठेका देने के पूर्व जो कीमत आंकी गयी, वह अनेक मामलों में त्रुटिपूर्ण थी। ५८ प्रतिशत ऋण सुविधा डायट्श मार्क में अदा करने का समझौता करके आयात के लिए आयातक देश की करेंसी में अदायगी की आम सरकारी नीति की उपेक्षा की गयी। बोफोर्स तोपों के रखरखाव की अतिरिक्त कीमत का भी मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि इन तोपों में खामियों की अधिक संभावना है। तोप के लिए खासकर बने गोला बारूद पर ४२.७३ करोड़ का जो अतिरिक्त खर्च आया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार उत्पादन लाइसेंस पाने पर भी कोई विचार नहीं किया गया।
- बोफोर्स तोपों का लाइसेंस द्वारा उत्पादन का फैसला उसके व्यापक वित्तीय और आर्थिक कीमतों के मूल्यांकन द्वारा नहीं किया गया। बोफोर्स ने निश्चित तारीख के नौ महीने बाद अप्रैल, १९८७ को जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश की उसे सरकार ने जनवरी, १९८८ तक मंजूर नहीं किया। इस देरी का सुरक्षा तैयारियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.

—प्रस्तुति : त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

प्रधानमंत्री ने कब क्या कहा ?

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, १८ अप्रैल, १९८७: कुछ ताकतें देश की सैन्य आपूर्ति में बाधा डालकर हमारी सुरक्षा क्षमताओं को कमजोर करना चाहती हैं।

लोकसभा, २० अप्रैल, १९८७: विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि १५५ एमएम तोपों का ठेका प्राप्त करने के लिए कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और आला फौजी अधिकारियों को रिश्वत दी गयी है। यदि इस बारे में वे कुछ सबूत पेश करें या दिशानिर्देश करें...यदि इसमें कुछ तथ्य पाया गया, तो अपराधी को—वह चाहे कितने ऊंचे ओहदे पर क्यों न हो—सख्त सजा दी जायेगी।

सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में, २७ अप्रैल, १९८७: स्वीडन ने मुझे खबर की है कि न तो कोई बिचौलिया था और न ही किसी को स्विस बैंक में पैसा ही दिया गया।

राज्यसभा में, २८ अप्रैल, १९८७: मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें स्वीडन सरकार से अब तक कोई विशिष्ठ जानकारी नहीं मिली है. हमें उन्हें जवाब देने का मौका देना चाहिए।

लोकसभा, २८ अप्रैल, १९८७: स्वीडिश तोप सौदे में स्व० ओल्फ पाल्मे और मौजूदा प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन से कोई कमीशन तय नहीं हुआ था।

लोकसभा, २८ अप्रैल, १९८७: मैं पुनः दोहराता हूं कि हम स्वीडिश सरकार की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस क्षण हमें वह प्राप्त होगी, हम कार्रवाई करेंगे—और राष्ट्र को दिखायेंगे कि हमने कार्रवाई की है।

मद्रास, २ अगस्त १९८७: बोफोर्स कुछ भी बताने को तैयार नहीं और जो लोग बोलना नहीं चाहते, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं।

नयी दिल्ली, ६ जुलाई, १९८७: स्वीडिश रिपोर्ट और संसद में की गयी घोषणा में कोई अंतर्विरोध नहीं है।

लोकसभा, ६ अगस्त, १९८७: संसद के भीतर और बाहर अनेक आरोप लगाये गये हैं। अफवाहों और बेबुनियाद संदेहों का इस्तेमाल करके देश और उसके नेतृत्व की छवि धूमिल की गयी है। मैं भारतीय लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच से स्पष्ट घोषणा करता हूं कि न मैंने, न मेरे परिवार में किसी ने इन सौदों में कोई लाभ उठाया है। यही सच है। मैंने दोनों सदनों में बार-बार कहा है कि यदि यह सिद्ध हो गया कि कोई व्यक्ति गैरकानूनी धन लेने का दोषी रहा है, तो कानून के तहत कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कांग्रेस और उसकी सरकार का सचाई के उजागर होने में वैसी ही दिलचस्पी है, जैसी किसी अन्य की। इस साझा काम में संसद के तमाम वर्गों को सहयोग करना चाहिए।

राजकोट ९ अगस्त, १९८७: यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विपक्ष की सचाई को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहा गया है कि वे संयुक्त संसदीय समिति में शिरकत के लिए रजामंद नहीं।

हैदराबाद ९ अगस्त, १९८७: हम अंत तक जांच करना चाहते हैं और हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है।

बीबीसी से बातचीत, १२ अक्तूबर, १९८७: हमने जितना पता लगाने का सोचा था, बोफोर्स ने उससे अधिक जानकारी दी है... जहां तक मेरी जानकारी है, भारत में किसी को धन नहीं दिया गया।

स्टाकहोम ४ नवंबर, १९८८: हमने बड़ी कोशिश की है। हमारी कोशिश खत्म नहीं हुई। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई निदेशक मोहन कात्रे श्री रिंगबर्ग और स्वीडिश नेशनल बैंक के लोगों से मिलने गये हैं।

—प्रस्तुति: विवेक शर्मा

तारिक अनवर

> सांसद तारिक अनवर ने जोड़ा, "इस्तीफे जनता की सहानुभूति हासिल करने का भोंडा राजनीतिक हथकंडा हैं। चुनाव मैदान में उतरने के लिए विपक्ष के पास कुछ अन्य था ही नहीं।"

डालने की योजना बनायी है। विपक्ष की इस मुद्दे पर स्थिति इतनी नाजुक है कि कांग्रेस नेता पीएन सुकुल के अनुसार, "इस्तीफे का नाटक बोफोर्स से अधिक पंचायत राज विधेयक में शामिल न होने के लिए किया गया है, क्योंकि इस विधेयक को न तो वह प्रत्यक्ष समर्थन देना चाहते थे और न मुखर विरोध करना।"

यदि सुकुल की बात सही है, तो लोकसभा से चाहे विपक्षी बच गये हों, किंतु राज्यसभा में उनकी संकटपूर्ण स्थिति बरकरार है। विधेयक पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है जो राज्यसभा में कांग्रेस के पास नहीं है। यदि वहां विपक्ष विधेयक का समर्थन करता है, तो कांग्रेस को जनता में यह प्रचारित करने का मौका मिलेगा कि जनता के हाथ सत्ता सौंपने की पहल उसने की है। यदि विपक्ष विधेयक का विरोध करता है, तो कांग्रेस मतदाताओं के सामने यह दलील पेश करेगी कि हम तो प्रगतिशील और जनकल्याणकारी कदम उठाना चाहते हैं, किंतु विपक्ष उसमें बाधक है।

कांग्रेसियों की मनःस्थिति: इस चौमुखी रणनीति के पश्चात भी कांग्रेस आश्वस्त नहीं है। यह इसी से उजागर है कि विपक्ष को छकाने, हराने के अन्य मार्ग तलाशने में भी वह जुटी हुई है, क्योंकि उसके मन में यह बात घर कर चुकी है कि जब तक विपक्षी इस्तीफे जैसा भारीभरकम नाटकीय लटका-झटका वह नहीं अपनायेगी, तब तक वह जनमत को अपने पक्ष में करने में पूर्ण सफल नहीं होगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एक विकल्प यह है कि विधेयकों को पारित कराने के बाद ९-१० अगस्त को लोकसभा भंग कर दी जाये, किंतु अधिकांश कांग्रेसी इसके विरुद्ध बताये जाते हैं। उनके अनुसार विपक्षी इस्तीफे के पूर्व यदि यह कदम उठाया जाता, तो कदाचित कारगर होता। किंतु इस्तीफा प्रकरण के बाद लोकसभा भंग करके अपेक्षित लाभ नहीं उठाया जा सकेगा, क्योंकि फिर शीघ्र चुनाव कराना लाजिमी हो जायेगा और इस समय हवा कांग्रेस के पक्ष में नहीं है।

अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि चुनाव में जितना अधिक अंतराल होगा उतना ही उनको लाभ होगा। एक, तो विपक्ष बोफोर्स की डुगडुगी अधिक दिन नहीं बजा पायेगा। दूसरे, इस अंतराल के दौरान विपक्ष में मल्लयुद्ध की संभावना भी बढ़ जायेगी और कांग्रेस स्वयं इस बीच कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चला नेकनीयती का परिचय दे, अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती है।

किसी जोरदार धमाके की तलाश ने कांग्रेस के कदम राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ा दिये हैं, ऐसा जानकार सूत्रों का दावा है। 'माया' को मिली विशिष्ट जानकारी के अनुसार अपनी मां श्रीमती गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सफल ऐतिहासिक कदम को याद करते हुए राजीव गांधी इस्पात और अल्युमिनियम के शीघ्र राष्ट्रीयकरण का लगभग मन बना चुके हैं। इस संबंध में आवश्यक कवायद-कसरत जोरशोर से जारी है। साथ ही चुनिंदा [illegible] व्यावसायिक घरानों पर छापे मारकर यह

सिद्ध करने की योजना भी है कि वर्तमान सरकार की यह मुहिम तत्कालीन वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की नहीं, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की थी। सूत्रों के अनुसार, टाटा स्टील के सर्वेसर्वा रूसी मोदी और आदित्य बिड़ला और उनके व्यावसायिक संस्थानों के उच्चाधिकारियों पर जांच-परख टीम की इस समय विशिष्ट अनुकंपा है। आगामी कुछ दिनों में यदि इन पर छापों की बौछार हो, तो आश्चर्य नहीं।

चुनावी लड़ाई निश्चित तौर पर संसद से सड़क पर आ गयी है। जीत के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों ही कोई भी हथकंडा छोड़नेवाले नहीं। फिलहाल, विपक्ष का पलड़ा कुछ भारी है, क्योंकि न केवल उसने मुद्दा हथिया लिया है, बल्कि कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए बाध्य किया है। विपक्ष को एकजुटता और सीएजी रिपोर्ट का जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो गया है, उसके सहारे वह जनता को यह बताने में सक्षम होगा कि अभी तक हम बोफोर्स घोटाले में राजीव सरकार के संलग्न होने की जो बात कहते आये हैं, उस पर स्वयं एक उच्च सरकारी संस्थान (सीएजी) ने अपनी मुहर लगा दी है। असम गण परिषद नेता दिनेश गोस्वामी के अनुसार, "इसका दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि जनमानस में यह प्रश्न अवश्य घर कर जायेगा कि क्या हम ऐसी सरकार और प्रधानमंत्री पर भरोसा कर सकते हैं जो अपनी काली करतूतों को ढकने-मूंदने के लिए संसद और झूठ दोनों को इस्तेमाल करते हैं।" 'माया' के इस सवाल पर कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को चुनाव तक घसीट सकेगा? गोस्वामी बोले, "ऐसे मुद्दे कभी भुलाये नहीं जाते। आपातकाल में सतह पर कोई आंदोलन नहीं छिड़ा था, बल्कि माहौल में खामोशी थी, किंतु चुनाव (१९७७ के) होते ही आपातकाल के जोरजुल्म की भरपूर सजा जनता ने सरकार को अपदस्थ करके दी थी। यही बात असम में भी देखने को मिली।"

इसके ठीक विपरीत राय कांग्रेसियों की है। उनके अनुसार कांग्रेस बनाम कांग्रेस का संघर्ष आज समाप्त हो चुका है और समूची पार्टी सर्वोच्च नेतृत्व के पीछे कतारबंद हो विपक्ष से लोहा लेने और चुनावी वैतरणी सफलतापूर्वक पार करने को कटिबद्ध है। नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने टिप्पणी की, "देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो गयी है। अब इस पर इस्तीफों जैसे नाटकीय कार्यों, प्रदर्शनों, बंद आदि का कोई असर नहीं पड़नेवाला। उसका चिंतन यथार्थवादी और वस्तुपरक हो गया है। वह जानती है कि भविष्य कांग्रेस के हाथों ही सुरक्षित रहेगा।"

व्यापारी वर्ग का रुख : कांग्रेसी आशा के पीछे यह जानकारी भी है कि व्यावसायिक वर्ग स्थिरता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को ही केंद्र में गद्दीनशीं देखना चाहता है। इस्तीफे प्रकरण के बाद शेयर बाजार में आयी हलचल ने उनके इस विश्वास को पुख्ता किया है। विपक्ष स्थिर सरकार नहीं दे सकेगा, इस पर जनता दल नेता राम विलास पासवान बोले, "लड़खड़ाहट एक बाल्यकाल में होती है, एक वृद्धावस्था में। बाल्यकाल में यह भविष्य में दौड़ने की तैयारी का संकेत होती है, तो बुढ़ापे में कब्रगाह की ओर बढ़ते कदमों का। विपक्ष और कांग्रेस की लड़खड़ाहट में यही फर्क है।"

विपक्ष के पास हारने को कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास हारने को बहुत कुछ है। विपक्ष की हौसला-अफजाई का कारण समीप दिखायी देता सत्तासुख है, तो कांग्रेस के सामने प्रश्न जीवन-मरण का है। इस कांटे की लड़ाई में निर्णायक मुद्दा यह होगा कि कौन अपनी बात जनता तक पहुंचाने, उसका विश्वास प्राप्त करने और अपने पक्ष में जनमत बनाने में कामयाब होता है। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक हंसते हुए बोले, "विपक्ष ने १५० प्रतिशत ऊर्जा तो पैदा कर दी है, किंतु खचड़ा ट्रांसमिशन लाइन (संसाधन) के चलते देखना यह है कि जनता के बीच वह कितने बल्ब (आशा) जला पाता है। कांग्रेस अपार संसाधनों से तो लैस है, किंतु उसके हजार वाट के बल्ब (राजीव गांधी) पर कालिख की मोटी परत चढ़ी है।"

—रंजना कक्कड़,

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

रामविलास पासवान

जनता दल के नेता रामविलास पासवान बोले, "लड़खड़ाहट एक बाल्यकाल में होती है, एक वृद्धावस्था में। बाल्यकाल में यह भविष्य में दौड़ने की तैयारी का संकेत होती है, तो बुढ़ापे में कब्रगाह की ओर बढ़ते कदमों का, विपक्ष और कांग्रेस की लड़खड़ाहट में यही फर्क है।"

क्या वीपी सिंह भी दोषी हैं ?

क्या बोफोर्स तोप सौदे के लिए वीपी सिंह भी जिम्मेदार हैं? रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत ने २६ जुलाई को लोकसभा में कहा है कि वित्तमंत्री के रूप में वीपी सिंह ने इस सौदे को मंजूरी दी थी, इसलिए इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। गृहराज्यमंत्री पी चिदंबरम ने तो २९ जुलाई को वीपी सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हैं और वित्त मंत्रालय की कार्यशैली के बारे में देश की जनता के सामने गलतबयानी कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कामकाज कैसे होता है, इसकी शिक्षा देते हुए भूतपूर्व वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी वीपी सिंह को आड़े हाथों लिया है। और तो और सौम्य और शालीन राजनीति के विश्वासी नारायण दत्त तिवारी को भी पहली दफा सीधे-साधे वीपी सिंह पर वार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मुखर्जी और तिवारी से बयान जारी करवाने का उद्देश्य यह जताना है कि वीपी सिंह यदि वित्तमंत्री के रूप में चाकचौबंद रहे होते, तो यह घपला नहीं होता। यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के नाते भी वीपी सिंह बोफोर्स सौदे की जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते।

इन आरोपों का जवाब वीपी सिंह यह कह कर देते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा के लिए बोफोर्स तोपों को आवश्यक बताया था, इसलिए वे देश की सुरक्षा की अवहेलना कैसे कर सकते थे। 'मेरी जिम्मेदारी इतनी ही थी कि मैं तोपों की खरीद के लिए धनराशि उपलब्ध करा दूं।"

सिद्धांततः यह माना जा सकता है कि वित्तमंत्री के नाते बोफोर्स सौदे की जिम्मेदारी वीपी सिंह पर भी आती है। लेकिन क्रूर यथार्थ यह है कि जब २४ मार्च, १९८६ को बोफोर्स सौदे पर दस्तखत हुए, तो राजीव गांधी मात्र प्रधानमंत्री ही नहीं, रक्षामंत्री भी थे। रोचक तथ्य यह है कि जब कांग्रेसी धन खर्च करनेवाले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते, तो धन देनेवाले व्यक्ति को जिम्मेदारी का अहसास करवाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? जब वीपी सिंह पर कांग्रसी आरोप लगाते हैं, तो राजीव गांधी पर बड़ा आरोप सीधे-सीधे लग जाता है, क्योंकि वीपी सिंह तो मात्र वित्तमंत्री थे, जबकि राजीव गांधी तो रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री दोनों थे। बड़ा अपराध किसका? ◆

बोफोर्स घटनाक्रम

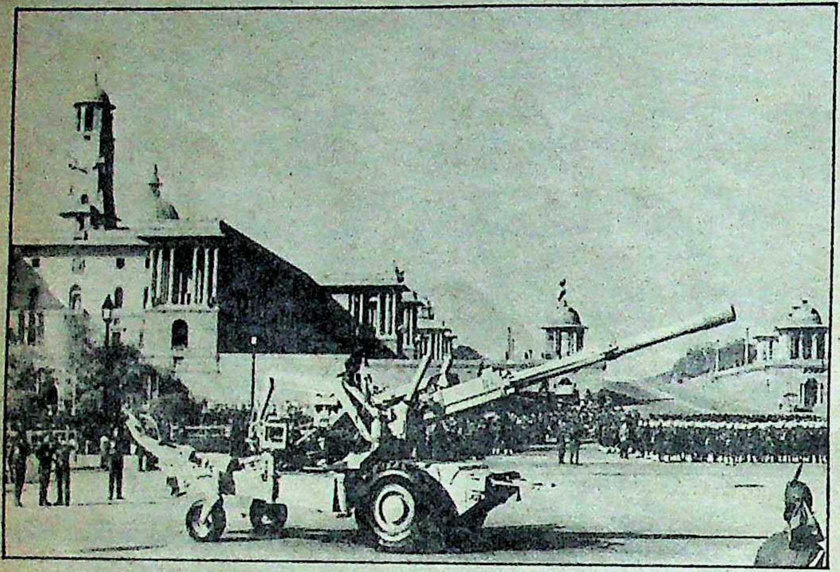

अक्तूबर, १९७९: चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में थल सेना अध्यक्ष ओपी मल्होत्रा ने भारतीय सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करनेवाली १५५ मिलीमीटर की मैदानी तोप की जरूरत की पेशकश की।

अगस्त, १९८०: १५५ मिलीमीटर की तोप खरीदने का फैसला।

सितंबर, १९८०: विभिन्न देशों की १५५ मिलीमीटर की ११ तोपों में से ८ तोपों का परीक्षण के लिए चयन।

दिसंबर, १९८२: सेना मुख्यालय ने परीक्षण करके पहली वरीयता में फ्रांस की सोफमा तोपों, दूसरी वरीयता में बोफोर्स तोपों को रखा। इसके बाद क्रमश: इंग्लैंड की इंटरनेशनल मिलीटरी सर्विस की तोपों और आस्ट्रेलिया की वोयेस्ट अल्पाइन तोपों का स्थान था।

अप्रैल, १९८४: मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने तोपों की खरीद के लिए हरी झंडी दी।

नवंबर, १९८५: बोफोर्स से आर्थिक, तकनीकी और स्वदेश में उत्पादन लायसेंस के संबंध में बातचीत करने के लिए समझौता समिति का गठन।

२० जनवरी, १९८६: रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट कि सोफमा और बोफोर्स—दोनों ही तोपें उपयुक्त हैं।

१२ मार्च, १९८६: रक्षा मंत्रालय ने बोफोर्स तोपें खरीदना तय कर दिया।

२१ मार्च, १९८६: सोफमा द्वारा अपनी तोपों की कीमत में ५.६ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा। बोफोर्स द्वारा १० तोपों को मुफ्त देने की पेशकश। लेकिन बोफोर्स तोपें खरीदने का फैसला ही अटल रहा।

२४ मार्च, १९८६: बोफोर्स को ४०० तोपें खरीदने का आदेश दे दिया गया। इकरारनामे पर दस्तखत।

१६ अप्रैल, १९८७: स्वीडिश नेशनल रेडियो ने अपने समाचार प्रसारण में रहस्योदघाटन किया कि गत वर्ष बोफोर्स कंपनी ने १७०५ करोड़ रुपए मूल्य की १५५ मिलीमीटर एफएच-७७ होवित्जर तोपों का भारत से सौदा हासिल करने के लिए कांग्रेस-इ के नेताओं को दलाली दी।

१७ अप्रैल, १९८७: स्वीडिश नेशनल रेडियो ने बताया कि उन्होंने बोफोर्स कंपनी के बैंक 'स्कैंडिनेविस्का ऐंस्किल्डा बैंकन' से पता लगाया है कि गत वर्ष (१९८६) नवंबर-दिसंबर में चार किश्तों में दलाली की ६ करोड़, ६० लाख रुपए की रकम भारतीय खातों में जमा करायी गयी। बोफोर्स के एक प्रवक्ता ने एसोएियेटेड प्रेस संवाद समिति को बताया कि भारतीय खातों में जमा करायी गयी रकम न तो दलाली थी और न ही सौदा हासिल करने के लिए दी गयी घूस। स्वीडन के आर्थिक मंत्रालय के सचिव कार्ल जोहान एबर्ग ने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री ओल्फ पाल्मे से साफ कह दिया था कि इस सौदे में कोई दलाल नहीं होगा।

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि स्वीडिश रेडियो का यह समाचार आधारहीन और झूठा है और भारत के राजनीतिक ढांचे को तहस-नहस करने की विदेशी साजिश की एक और कड़ी है।

१८ अप्रैल, १९८७: भारत स्थित स्वीडिश राजदूत ऐडल स्टाम ने भारत के विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह को स्वीडिश सरकार का संदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि बोफोर्स तोप सौदे में कोई दलाल नहीं था।

२१ अप्रैल, १९८७: रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह ने राज्यसभा को बताया कि यदि कोई दलाली दी गयी है, तो हम इससे जुड़े हर सवाल-क्या, कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा यह क्यों दी गयी—का जवाब हासिल करेंगे।

२५ अप्रैल, १९८७: बोफोर्स कंपनी के उपाध्यक्ष और भारतीय सौदे के समन्वय अधिकारी बेरटिल ब्रेडिल ने एक भेंटवार्ता में बताया कि विन चड्ढा कुछ समय के लिए हमारा एजेंट रह चुका है, लेकिन जब १९८५ में भारत सरकार ने आदेश दिया कि रक्षा सौदों में कोई दलाल नहीं रहेगा, तो उसके बाद वह हमारा सलाहकार बन गया।

२७ अप्रैल, १९८७: सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में राजीव गांधी ने कहा कि उन्हें स्वीडन सरकार ने बताया है कि बोफोर्स तोप सौदे में कोई दलाल नहीं था।

२८ अप्रैल, १९८७: स्वीडन के प्रधानमंत्री कार्लसन ने तत्काल इस बात का खंडन किया कि राजीव गांधी ने बोफोर्स के संबंध में उनसे कोई जानकारी मांगी है।

२९ अप्रैल, १९८७: रक्षा मंत्री केसी पंत ने लोकसभा में सूचना दी कि स्वीडिश सरकार अपने नेशनल आडिट बोर्ड के जरिए दलाल का पता लगा रही है।

३० अप्रैल, १९८७: राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बोफोर्स एवं अन्य रक्षा सौदों से संबंधित फाइलें तलब कीं।

५ मई, १९८७: मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने राष्ट्रपति के पत्र पर विचार कर जो उत्तर तैयार किया, उसके अनुसार सरकार ने बोफोर्स मामले पर और जानकारी देने से इनकार कर दिया।

७ मई, १९८७: राज्य सभा में अध्यक्ष आर वेंकटरमण (अब राष्ट्रपति) ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गयी जानकारी प्रधानमंत्री द्वारा न देने के सवाल को उठाने की अनुमति नहीं दी, तो आल इंडिया अन्नाद्रमुक और नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों को छोड़कर सारे विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।

८ मई, १९८७: राज्यसभा में जब राजीव गांधी ने बताया कि स्वीडन सरकार से उन्हें कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है, तो विपक्षी सदस्यों ने सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में दिये गये उनके भाषण का हवाला देते हुए उनके

परस्पर विरोधी वक्तव्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। इसके जवाब में कहा गया कि राजीव गांधी की बातचीत स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री ओल्फ पाल्मे से हुई थी न कि वर्तमान प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन से। राजीव गांधी ने कहा कि अखबारों में यह खबर तोड़मरोड़ कर छापी गयी है।

१६ जुलाई, १९८७: भारत सरकार ने बोफोर्स कंपनी से पत्र लिखकर पूछा कि क्या उसने यह सौदा हासिल करने के लिए किसी को दलाली दी?

१९ जुलाई, १९८७: प्रेट्र के अनुसार भारत सरकार ने अमरीका के अखबारों में विज्ञापन छपवाया कि बोफोर्स के कथित एजेंट विन चड्ढा २२ जुलाई को दिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समक्ष उपस्थित हों।

२९ जुलाई, १९८७: बोफोर्स सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन। विपक्ष द्वारा समिति के बहिष्कार और सचाई जानने के लिए अपना प्रतिनिधि स्वीडन भेजने की पेशकश।

८ अगस्त, १९८७: लोकसभा में राजीव गांधी ने घोषणा की कि न तो मेरा और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य का बोफोर्स तोप सौदे से कोई संबंध है।

१२ अगस्त, १९८७: रक्षामंत्री केसी पंत ने बताया कि बोफोर्स कंपनी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया है कि उसने तोपों का सौदा प्राप्त करने के लिए किसी को रिश्वत या दलाली नहीं दी है।

१८ अगस्त, १९८७: विश्वनाथ प्रताप सिंह सहित सौ विपक्षी नेता दिल्ली स्थित स्वीडिश दूतावास गये और स्वीडिश प्रधानमंत्री कार्लसन को लिखे संयुक्त पत्र के द्वारा बोफोर्स तोप सौदे के दलालों के नाम उजागर करने की मांग की।

१९ अगस्त, १९८७: अमरीकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि भारत सरकार ने विन चड्ढा को अमरीका से यहां भेजे जाने के संबंध में विधिवत आवेदन नहीं किया है और विन चड्ढा ने कोई अमरीकी कानून नही तोड़ा है इसलिए वह विन चड्ढा को भारत जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

२० अगस्त, १९८७: भारत सरकार द्वारा स्वीडन स्थित अपने राजदूत को बोफोर्स सौदे के संबंध में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो से पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश।

३ सितंबर, १९८७: स्वीडन के प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन द्वारा बोफोर्स सौदे की जांच के लिए भारत के विपक्षी सदस्यों को स्वीडन आने की इजाज़त देने से इनकार। स्वीडन के विदेश मंत्री स्टेन एंडरसन ने घोषणा की कि उनका देश बोफोर्स तोप सौदे में स्वीडन के नेशनल आडिट ब्यूरो द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट की जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं देगा।

१८ सितंबर, १९८७: बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष मोरबर्ग ने संयुक्त संसदीय समिति से कहा कि न तो प्रधानमंत्री और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई कमीशन दिया गया। बहरहाल, उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपने एजेंट विन चड्ढा को १९७८ से १९८५ तक की गयी सेवाओं के लिए और अपना कारबार समेटने (वाइंडिंग अप) के सिलसिले में ५७ करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

२९ सितंबर, १९८७: पोखरन में सुरक्षा मामलों की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों के सामने बोफोर्स तोपों का चलाकर प्रदर्शन किया गया।

२६ फरवरी, १९८८: बोफोर्स सौदे की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल ३० अप्रैल, १९८८ तक बढ़ा दिया गया।

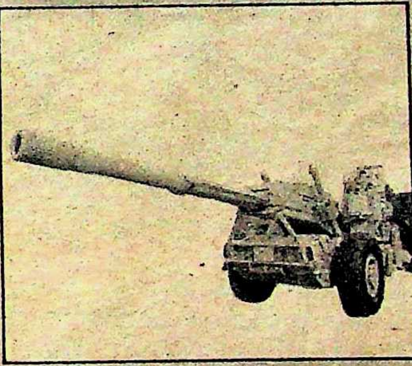

२६ अप्रैल, १९८८: संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी ४०० पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में भारत सरकार को हर आरोप से बरी करते हुए कहा है कि इस सौदे में किसी को कोई दलाली नहीं दी गयी और तोप चयन की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट में कहा गया कि बोफोर्स कंपनी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है और कानूनन बोफोर्स कंपनी को कोई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तथा ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जो बताते कि किसी भारतीय या प्रवासी भारतीय को कोई भुगतान किया गया।

२७ अप्रैल, १९८८: बोफोर्स के एक पूर्व प्रमुख अधिकारी मार्टिन आर्दबो ने कहा कि बोफोर्स तोप सौदे के संबंध में जो भुगतान किया गया, वह वाइंडिंग अप (कामकाज समेटने का) चार्ज था और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भुगतान प्राप्त करनेवाले भारतीय नागरिक थे।

१२ मई, १९८८: भूतपूर्व रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह ने राज्य सभा में मांग की कि बोफोर्स कंपनी ने बोफोर्स तोपों का सौदा हासिल करने के लिए तीन फर्मों को जो ६६ करोड़ रुपए की दलाली दी है, उसे बोफोर्स कंपनी से वापस वसूला जाये, क्योंकि यह भारतीय धन है। सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया।

१३ मई, १९८८: रक्षा राज्यमंत्री पी चिदंबरम ने राज्य सभा में स्वीकार किया कि बोफोर्स नें तीन कंपनियों को अपना कारबार समेटने के एवज में भुगतान किया था, लेकिन यह भुगतान बोफोर्स से तोपों का सौदा करने के पूर्व हुआ था, अतः इसे बोफोर्स तोप सौदे मे दी गयी दलाली नहीं कहा जा सकता। रक्षामंत्री केसी पंत ने विपक्षी सांसदों से कहा कि अब वे बोफोर्स दलाली के मामले को एक समाप्त हुआ अध्याय मान लें।।

११ अप्रैल, १९८९: अंग्रेजी दैनिक 'हिंदू' ने ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किये, जिनसे पता चलता था कि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली दी गयी थी।

८ मई, १९८९: स्विट्जरलैंड सरकार को बोफोर्स तोप सौदों के सिलसिले में भुगतान हुई कथित दलाली और दलाल का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा पहली बार पत्र प्रेषित।

२१ मई, १९८९: स्वीडन की संवैधानिक मामलों की समिति ने भारत और बोफोर्स कंपनी के बीच हुए तोप सौदे की जांच के बाद प्रस्तुत २०० पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा है कि बोफोर्स ने यह सौदा करके स्वीडन का कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात की कोई जांच नहीं की गयी और न ही इसकी चर्चा हुई कि बोफोर्स ने यह सौदा हासिल करने के लिए किसी को दलाली दी थी या नहीं।

१८ जुलाई, १९८९: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार बोफोर्स सौदे की १८ पृष्ठीय आडिट रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत। खरीदी के हर पहलू-समझौते की शर्तों, गुणवत्ता की परख, बारूद की क्वालिटी, तोपों की आपूर्ति आदि हर मामले में सरकार पर गंभीर आरोप।

१९ से २१ जुलाई, १९८९: विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार से इस्तीफे की मांग।

२३ जुलाई, १९८९: आंध्र भवन (दिल्ली) में एनटी रामाराव के नेतृत्व में १२ विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय।

२४ जुलाई, १९८९: ७३ विपक्षी सांसदों द्वारा, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा। अन्य ३५ विपक्षी सांसदों द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा। ■

शक्ति दीक्षा समारोह

अयोध्या में दहशत

अयोध्या में कुबेर टीले पर गत १२ और १३ जुलाई को आयोजित शक्ति दीक्षा समारोह में राम जन्मभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित कर देने की दीक्षा लेनेवालों की संख्या तेज वर्षा के कारण यद्यपि बेहद कम थी, लेकिन वक्ताओं ने इस समारोह में जो आग उगली और जैसी योजनाओं की घोषणा की, उनसे जाहिर हो जाता है कि आनेवाले दिनों में दहशतजदा अयोध्या और फैजाबाद में माहौल और उबाल खायेगा। क्या पुलिस और प्रशासन इस आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है?

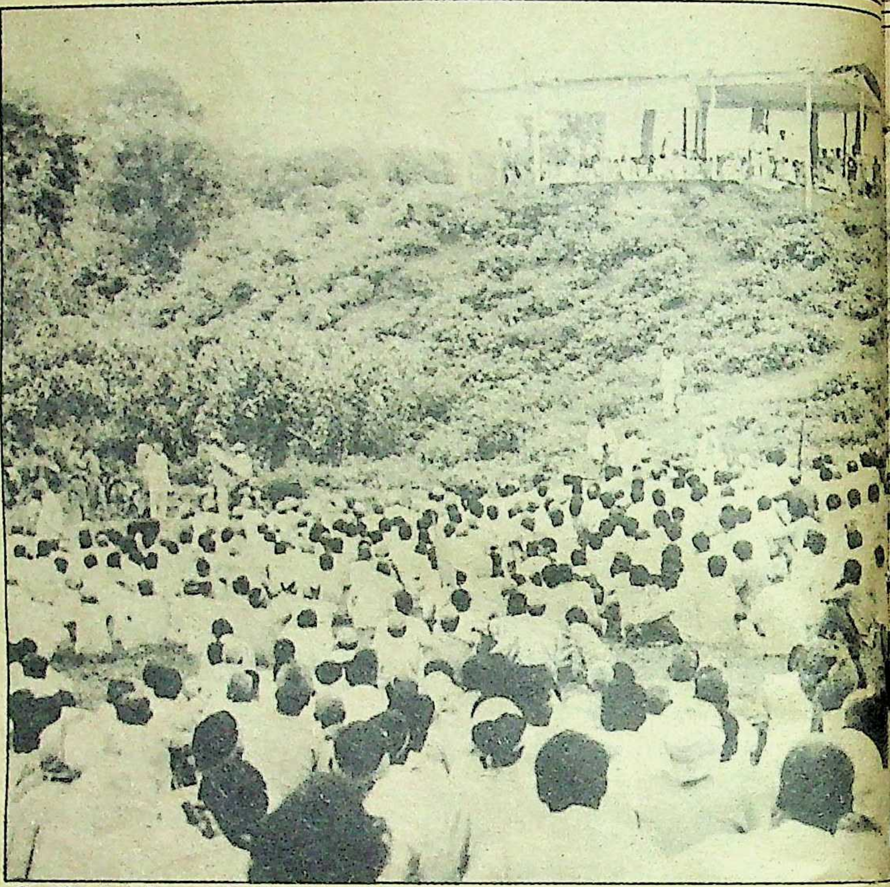

बलिदानी जत्था : दीक्षा समारोह में बजरंग दल के कार्यकर्ता

आगामी ९ नवंबर को अयोध्या में राम-जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की घोषणा से राम-जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में तल्खी आने और सांप्रदायिक उन्माद भड़कने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। यह विवाद क्या-क्या मोड़ ले सकता है, इसका अनुमान लगाकर, न-केवल अयोध्या और फैजाबाद में चिंता जाहिर की जा रही है, वरन् विवाद से सम्बद्ध दोनों संप्रदायों के लोग, पुलिस और प्रशासन स्थिति का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से फैजाबाद जिले में भारी वर्षा हो रही है। वर्षा के बीच ही बजरंग दल ने जब १२ और १३ जुलाई को अयोध्या के कुबेर टीले पर शक्ति दीक्षा समारोह आयोजित करने का फैसला किया था, तब उसने सोचा न होगा कि तेज वर्षा उसके रंग में भंग डाल सकती है। लिहाजा, जहां उम्मीद थी कि इस समारोह में २५ हजार कार्यकर्ता एकत्र होंगे, वहीं उनकी उपस्थिति डेढ़-दो हजार के आसपास रही। समारोह में स्वामी चिन्मयानंद ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और बाबर की औलादों से कोई समझौता न करने पर जोर दिया, तो राजस्थान के स्वामी धर्मेंद्र ने धमकी दी कि राम मंदिर के लिए आनेवाली शिलाओं को यदि किसी ने रोकने को कोशिश की, तो नरमुंडों की दीवारें चुनी जायेंगी और खून से गारे का काम लिया जायेगा।

शक्ति दीक्षा समारोह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के सेवा-निवृत्त पुलिस महानिदेशक श्रीशचन्द्र दीक्षित ने बलिदान और शक्ति की दीक्षा लेनेवाले कार्यकर्ताओं और साधु-महात्माओं का स्वागत किया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी वामदेव ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि परिवार नियोजन, सिविल कोड आदि सब सरकारी कायदे कानून हिंदुओं के लिए ही बनाये जाते हैं। धर्मांतरण भी हिंदुओं को ही झेलना पड़ता है। हिंदू समाज अब तक सब कुछ सहता चला आया, पर अब वह संघर्ष करेगा। उन्होंने हुंकार और शंखनाद के बीच सब कार्यकर्ताओं से हाथ उठाकर, शपथ दिलायी, "(१) मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान श्रीकृष्ण, शिवशंकर, बजरंगबली, भारतमाता और हिंदू धर्म की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र की सेवा और संरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और (२) मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विदेशी हमलावर बाबर द्वारा ध्वस्त श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनःप्रतिष्ठा के लिए तन, मन और धन से समर्पित रहूंगा।"

सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा : स्वामी वामदेव

भावी योजनाएं : सम्मेलन में भाग लेनेवालों में महंत अवैद्यनाथ, अशोक सिंघल, बैकुंठलाल शर्मा, इंद्रराज सिंह भीखा, ऋतम्भरा देवी, उमा भारती, रामानुजाचार्य, परमहंस रामचंद्रदास, महन्त नृत्यगोपालदास आदि प्रमुख थे। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये। आगामी १७ सितंबर से इंद्रप्रस्थ धर्मयात्रा शुरू करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय नेताओं के विचारों में परिवर्तन लाना है। इस यात्रा में १००० संत-महंत भाग लेंगे। २२ सितंबर को दिल्ली के बोट क्लब पर हिंदू महासम्मेलन होगा।

अशोक सिंघल का कहना है कि पौने छह लाख गांवों की जनता शिलापूजन के लिए निकलेगी। शिलाएं विकास खंड और जिलों से

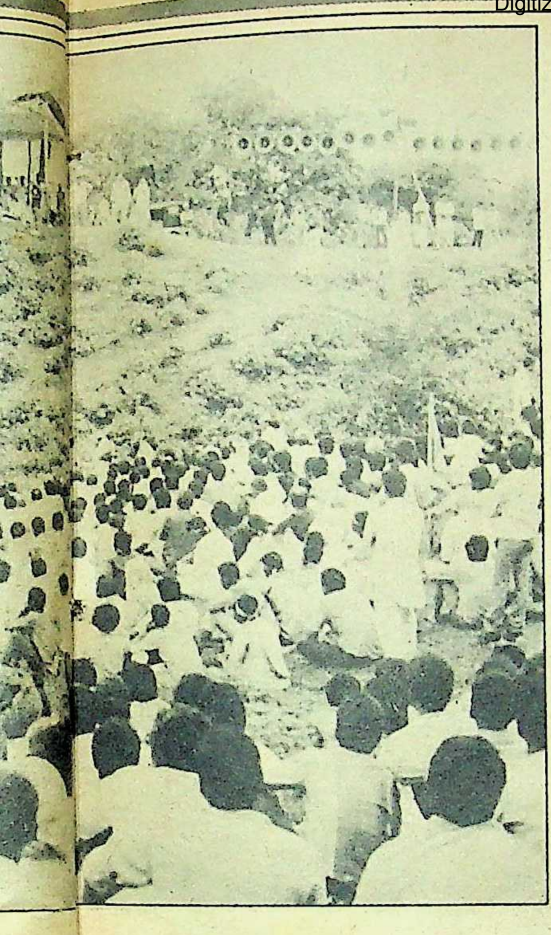

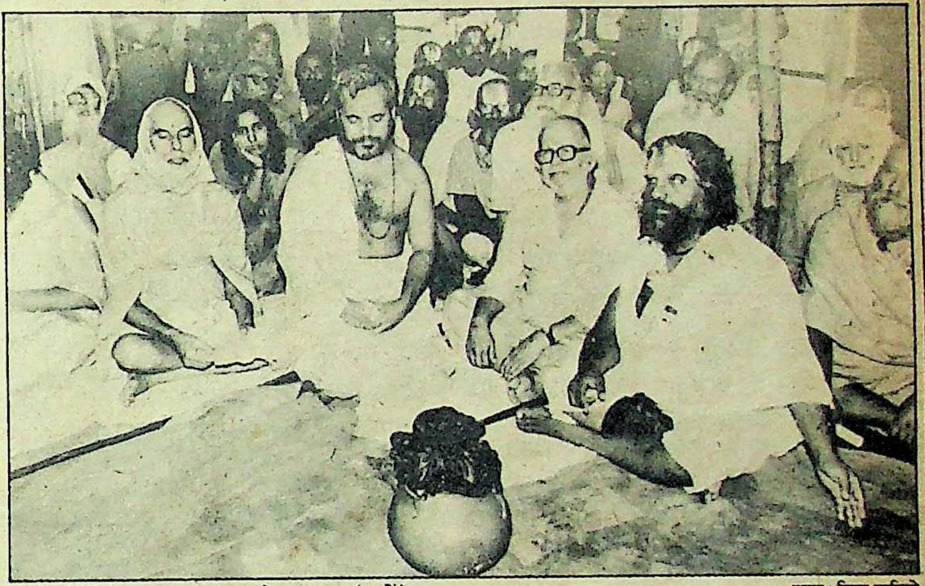

अयोध्या में नेतृत्व : महंत नृत्य गोपालदास (दायें)

छाया : विष्णु स्टूडियो

होते हुए अयोध्या पहुंचायी जायेंगी। लंदन में भी २६-२७ अगस्त को विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें ३५० हिंदू संस्थाएं सहयोग दे रही हैं।

अशोक सिंघल का दावा है कि २५ करोड़ हिंदू हमारे साथ हैं। हम छात्रों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय के दीना अवस्थी के नेतृत्व में एक समिति बनी है जो छात्रों को जन्मभूमि आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी। १५ सितंबर को देश भर के छात्र कक्षाएं छोडकर राम-जन्मभूमि दिवस मनायेंगे। लेकिन अभी तक राम-जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के कर्णधारों को स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का किस तरह से सामना करना है, इसलिए सभी अलग-अलग रंग-ढंग के बयान दे रहे हैं। ज्ञातव्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी ८ नवंबर को अयोध्या में विशाल रैली निकालने की तैयारी कर रही है। यह पूछे जाने पर कि इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? अशोक सिंघल कुछ परेशान से हुए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, "सड़कों पर निबटा जायेगा।" बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच से एक हट्टा-कट्टा कार्यकर्ता बोल उठा, "आखिर हम किस दिन के लिए हैं?" अशोक सिंघल का कहना है कि यदि मुसलमान, राम को राष्ट्रनायक मान लें, तो हिंदू जन्मभूमि-मस्जिद विवाद समाप्त करके वहां राष्ट्रीय स्मारक बनाने को तैयार हैं। लेकिन जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैद्यनाथ इससे सहमत नहीं। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। महंत अवैद्यनाथ अपने आंदोलन को अहिंसक और इससे सम्बद्ध कार्यकर्ताओं को सत्याग्रही बताते हैं। पर उमा भारती का कहना है कि मंदिर के काम में बाधा डालनेवालों का सिर फोड़ दिया जायेगा।

जन्मभूमि आंदोलन के पैसे-कौड़ी का हिसाब बड़ा गुप्त है। खर्च का सारा प्रबंध राम-जन्मभूमि न्यास करता है। न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास हैं। यह पूछने पर कि न्यास के पास कुल कितनी रकम है, परमहंस कहते हैं कि कोई पैसा नहीं है। लेकिन महंत अवैद्यनाथ कहते हैं, "पैसे का मामला है न, इसे हमेशा गुप्त रखा जाता है। बस इतना जान लो कि पैसे की कमी नहीं है।"

दहशत का माहौल : बात ठीक भी है। न पैसे की कमी है और न कार्यकर्ताओं की। जब ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं, तो छिपकर आग लगाने और उपद्रव करानेवाले तत्व भी सक्रिय होने लगते हैं। अयोध्या और फैजाबाद में पिछले कुछ दिनों में रकाबगंज, रतिया, रीडगंड आदि में बम-विस्फोट हुए हैं। एक मास के भीतर १३ लाशें बरामद हुई हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फैजाबाद के गुरुनानकपुरा में गत ७ जुलाई को सरदार निरंजन सिंह के घर के बाहर बम फेंका गया। यह अफवाह भी फैली कि १२-१३ जुलाई की रात में कोतवाली के पास तीन गायें मरी पायी गयीं।

इन घटनाओं से नगर में दहशत होना स्वाभाविक है। जिला अधिकारी सुरक्षा के प्रति विशेष चौकस हैं। शक्ति दीक्षा समारोह के दौरान किसी भी सम्भाव्य स्थिति से निबटने के लिए १५ कंपनी सशस्त्र पुलिस, ५०० होमगार्ड बल ५०० कांस्टेबल, १०० उपनिरीक्षक, १२ राजपत्रित अधिकारियों और खुफियाकर्मियों को अयोध्या और फैजाबाद में विशेष रूप से तैनात किया गया था। जिला अधिकारी रामशरण श्रीवास्तव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरभजन सिंह इस बात से संतुष्ट नजर आये कि शक्ति दीक्षा के दो दिन ठीक-ठाक गुजर गये।

पर अयोध्या और फैजाबाद के नागरिक बहुत आश्वस्त नजर नहीं आते। मुस्लिमबहुल रीडगंज, पुरानी सब्जी-मंडी, कसाईबाड़ा, हसनू कटरा और चौक में शक्ति दीक्षा समारोह के दो दिन काफी दहशत थी। उनकी दुकानें बंद थीं। हो सकता है, दुकानें ईदुज्जुहा के कारण बंद रही हों, पर हिंदुओं ने भी अपनी दुकानें बंद रखीं। लोगों को अशान्ति फूट पड़ने का भय घेरे रहा। आतंकित लोगों ने अपने घरों में आवश्यक वस्तुएं जमा करना शुरू कर दिया था।

अयोध्या और फैजाबाद की जनता इस मंदिर-मस्जिद विवाद को कतई पसंद नहीं करती। हिंदू और मुसलमान दोनों एक या दूसरे पक्ष के शक्ति प्रदर्शन से चिढ़कर कहते हैं कि जन्मभूमि की चिंता यदि हमें नहीं है, तो इन बाहरवालों को क्या होगी जो बसों में भरकर बाहर से आते हैं और हिंदू-मुसलमान सद्भाव के दूध में खटास डालकर चलते बनते हैं? घर हमारे जलते हैं, बच्चे-बूढ़े हमारे हलाक होते हैं।"

शक्ति दीक्षा समारोह के बाद अयोध्या और फैजाबाद के नागरिकों की एक बैठक नागरिक परिषद के तत्वावधान में दिनेश महेश्वरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सब पक्षों ने एक स्वर से मांग की, "हमें मंदिर-मस्जिद नहीं, शांति चाहिए।"

—अयोध्या से भास्कर दुबे

श्रीगांधी आश्रम

संस्था मालामाल, कर्मचारी खस्ताहाल

खादी ग्रामोद्योग के समान ही देश में ग्रामीण-आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीगांधी-आश्रम नामक संस्था कार्यरत है, लेकिन आश्चर्य है कि जहां खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत चलनेवाली संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं गांधी-आश्रम के कर्मचारी जिस आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। १९५७-५८ में गांधी-आश्रम के कार्यकर्ताओं को वही ८० रुपए मासिक वेतन मिलता था, जो एक प्राथमिक शिक्षक, सिपाही अथवा फौजी को दिया जाता था, लेकिन आज जहां इनके वेतन एक-डेढ़ हजार रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं, वहीं गांधी-आश्रम का कर्मचारी बमुश्किल १२५ से १६५ रुपए के मूल वेतन में ही संतुष्ट रहने के लिए मजबूर है, जबकि गांधी-आश्रमों की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा पक्षपात क्यों हुआ ?

गांधीजी के नाम पर चलनेवाले गांधी-आश्रमों का वातावरण आजकल बहुत अशांत और उद्वेलित है। गांधीवादी अब बगावत पर उतारू हैं। अन्य संगठित औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह वे अनशन, धरना और हड़ताल करने को बाध्य हैं। गांधी-आश्रम, देहरादून के केंद्रीय वस्त्रागार, धामपुर के कार्यकर्ताओं का आंदोलन तो इतना उग्र हो गया है कि वस्त्रागार के प्रबंधक ओमप्रकाश गुप्त को ३० कर्मचारियों के नाम समाचारपत्रों में नोटिस निकलवानी पड़ी कि वे यथाशीघ्र काम पर लौट आयें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक की कार्रवाई करनी होगी।

इस प्रसंग में दिलचस्प बात यह है कि कहने-बोलने में तो गांधी-आश्रम में काम करनेवालों को कार्यकर्ता कहा जाता है, पर नोटिस में उन्हें कर्मचारी माना गया है। एक व्यक्ति को कहीं कार्यकर्ता और कहीं कर्मचारी कहना उस पाखंड का नमूना है जो इन गांधी-आश्रमों में बरता जाता है। कार्यकर्ता बताकर उन्हें १२५ रुपए से १६५ रुपए मासिक वेतन पर काम शुरू करने को बाध्य किया जाता है। कुल-मिलाकर एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार ४०० से ५५० रुपए मासिक तक वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में किसी भी श्रमिक को प्रतिदिन १६.५० रुपए से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। पर, गांधी-आश्रम के कार्यकर्ता यदि औसत से १३-१४ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलनेवाली मजदूरी पर काम करने को बाध्य किये जाते हैं, तो वजह यही हो सकती है कि वे गांधीजी के अनुयायी हैं।

पक्षपात: वर्ष १९५७-५८ में ग्रामसेवक का वेतन जो अब ग्राम विकास अधिकारी है, ११० रुपए, प्राथमिक अध्यापक का ८० रुपए, पुलिस कांस्टेबल का ८० रुपए और सैनिक का वेतन ९० रुपए था। उस समय गांधी-आश्रम के कार्यकर्ता को भी ८० रुपए मासिक दिया जाता था। वेतन की दृष्टि से लगभग समान स्तर पर होने के अतिरिक्त गांधी-आश्रम से सम्बद्ध व्यक्ति को खादी कार्यकर्ता होने का आदर भी मिलता था। पर आज स्थिति बदल गयी है। खादी और गांधी दोनों में ही पहले जैसी चमक नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ७५० रुपए निर्धारित कर दिया गया है। खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत चलनेवाली संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष अन्य सब सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। पर गांधी-आश्रम के कार्यकर्ता को आज भी १२५ से १६५ रुपए मूल वेतन पर ही गुजारा करना पड़ता है।

भव्य भवन: देहरादून स्थित गांधी आश्रम का क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश का गांधी-आश्रम २९ क्षेत्रों में विभक्त है। ये क्षेत्र हैं—मुरादाबाद, बरेली, काशीपुर फार्म, हलद्वानी, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, हापुड, बुलंदशहर, शिकोहाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, जैदपुर, झांसी, अकबरपुर, आजमगढ़, सैदपुर, देवरिया, वाराणसी तथा देहरादून क्षेत्र। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। इनके अतिरिक्त पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में श्रीगांधी-आश्रम की शाखाएं हैं। आश्रम क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र में ८० से लेकर ४५० तक कार्यकर्ता कांम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त प्रत्येक में मंत्री, संचालक, प्रधानमंत्री तथा इनके अधीनस्थ कर्मचारियों की एक लंबी फौज कार्यरत है। इन २९ क्षेत्रों से लगभग ११००० कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से तथा इसके दूने कार्यकर्ता परोक्षरूप से सम्बद्ध हैं। इनमे बुनकर, धुनहे, जुलाहे, वाहन-चालक, वाहन-सहायक आदि सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार गांधी-आश्रमों से

संघर्ष जारी रहेगा :
चंद्रिका प्रसाद यादव

कार्यकर्ता अपने साथ होनेवाले जुल्मों और ज्यादतियों के लिए न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकते। गांधीजी का नाम जुड़ा होने के कारण सरकार भी इन संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से कतराती है।

प्रबंधकों ने हाथ ही तोड़ दिया :
सियाराम यादव

सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या ५० हजार तक पहुंच जाती है।

शोषण और जुल्म : गांधी-आश्रमों में काम करनेवालों पर संस्था के प्रधानमंत्री द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होते हैं। कार्यकर्ता अपने साथ होनेवाले जुल्मों और ज्यादतियों के लिए न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकते। गांधीजी का नाम जुड़ा होने के कारण सरकार भी इन संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से कतराती है। यही वजह है कि प्रबंधकों ने अब तक मनमाने ढंग से गांधी-आश्रम क्षेत्रों से २००० कार्यकर्ताओं को हटाया है।

मंत्री और संचालकों की गाय-भैंसों का गोबर उठाना, चौका-बासन करना और स्कूटर की धुलाई से लेकर घर की धुलायी-सफायी तक, सब कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी में शामिल है। आरोप है कि जरा सा भी विरोध करने पर इन्हें लात-घूंसे तक खाने पड़ते हैं। तरह-तरह से अपमानित करने और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है।

देहरादून क्षेत्र के कार्यकर्ता विजयपाल सिंह की नियुक्ति १९८४ में ६६ रुपए मूल मासिक वेतन पर हुई थी। आजकल उनका वेतन १५० रुपए है। वे बताते हैं, "भंडार और स्टोर में काम करने के अतिरिक्त मुझे संचालक और मंत्री की गाय-भैंसों का भी इंतजाम करना पड़ता है। आश्रम संचालक रामकिशोर अग्निहोत्री की गाय के चारे-पानी का इंतजाम न करने पर मुझे मुअत्तल करने की धमकी दी गयी।" एक अन्य कार्यकर्ता शेषमणि का कहना है, "प्रातः ५ बजे उठकर क्षेत्रीय मंत्री विद्याचरण त्रिवेदी के कमरे की सफायी करनी पड़ती है। फिर स्कूटर धोना पड़ता है। गायों का गोबर उठाना और झाड़ू-पोंछा करना मेरी नियति बन चुकी है। बाराबंकी के शीतल सिंह की नियुक्ति १९५६ में २३ रुपए माहवार पर की गयी थी। इस समय उन्हें ५०० रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। रायबरेली के कमला सिंह २३ वर्ष तक सेवा करने के बाद अब ६७५ रुपए प्रतिमास पाते हैं।

आगरा के क्षेत्रीय गांधी-आश्रम प्रबंधक प्रभुनारायण गुप्त के नाम से एक घोटाला कांड काफी चर्चित है। उन्होंने कासगंज के भंडार-प्रबंधक सीताराम सिंह से मिलकर दो लाख रुपए का घोटाला किया और दोष कार्यकर्ताओं के सिर मढ़ दिया। आरोप में जान डालने के लिए गोदाम को नष्ट करा दिया गया। सचाई का पता चलने पर क्षेत्रीय संचालक विश्वनाथ पांडे ने क्षेत्रीय मंत्री को लताड़ा और प्रबंधक सीताराम को निलंबित कर दिया।

आंदोलन पर आमादा कर्मचारी : गांधी-आश्रमों के असंतुष्ट कर्मचारियों ने वैसे तो आंदोलन का रास्ता १९६० में पकड़ा था। पर, अब इसे आजमगढ़ के संतजी उर्फ जितेंद्र नाथ सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। वे इस समय गांधी-आश्रम कोपागंज भंडार (मऊनाथ भंजन) में कार्यरत हैं और श्री गांधी-आश्रम कर्मचारी वेतन संघर्ष समिति के संयोजक हैं। उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन काफी आगे बढ़ गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में प्रबंधकों की मनमानी से कार्यकर्ता आंदोलित हैं। देहरादून क्षेत्र में धामपुर की स्थिति काफी विस्फोटक है। देहरादून क्षेत्र में डेढ़ दर्जन कार्यकर्ताओं के स्थानांतरण या मुअत्तली की कार्रवाई चल रही है। देहरादून के कार्यकर्ता गुलाब चंद्र राय को देहरादून से टिहरी स्थानांतरित किया गया है। गिरीश चंद्र पांडे को देहरादून से उत्तरकाशी, अखिलानंद राय को देहरादून से पौड़ी, रवींद्रराय को धामपुर से पौड़ी, देवेंद्र मिश्र को नगीना से पौड़ी, तेज बहादुर सिंह को धामपुर से उत्तरकाशी, रामशिव यादव को बिजनौर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया है। ये सब गांधी-आश्रम कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। मुअत्तली की सूची में तिलकराज और मर्यादामणि त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। एसोसिएशन के इन कार्यकर्ताओं को स्थानांतरित करने के बाद मुअत्तल कर दिया गया।

एसोसिएशन के मंत्री चंद्रिका यादव को एक मास के भीतर पलटन बाजार भंडार से आढ़त बाजार और फिर आढ़त बाजार से पलटन बाजार भेजा गया। देहरादून एसोसिएशन के अध्यक्ष सियाराम यादव का प्रबंधकों ने हाथ तोड़ दिया, जिससे आंदोलन शुरू हुआ। बाद में प्रबंधकों और एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ कि कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने के कारण न तो उत्पीड़ित किया जायेगा और न उनका स्थानांतरण किया जायेगा। पर बाद में इसके प्रतिकूल व्यवहार किया गया।

गांधी-आश्रमों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। प्रायः सभी इकाइयां लाभ में चल रही हैं। प्रबंधक यदि चाहें, तो कर्मचारियों की मांगें मानकर अशांति को समाप्त कर सकते हैं। पर प्रबंधक अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। कर्मचारी भी अब पशुओं जैसा व्यवहार बर्दाश्त करने की क्षमता खो चुके हैं।

—लखनऊ ब्यूरो

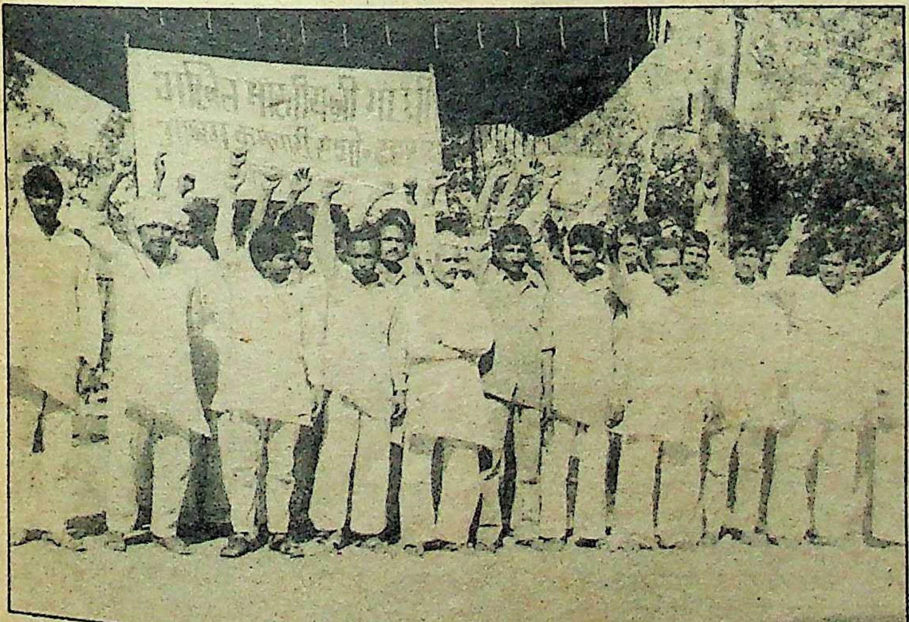

गांधी के पदचिह्नों पर : धामपुर (बिजनौर) गांधी आश्रम के आंदोलनरत कर्मचारी

गैस पीड़ित

घाव पर नमक

मिक ने कितनों को मारा, कितनों को अपंग किया, यह बात दब गयी है और उभर आयी है यह बात कि सरकार की आपदा राहत नीति पूरी तरह अपंग है और सरकारी तंत्र पूर्णतः अनैतिक। तभी तो भोपाल गैस त्रासदी की चपेट में आकर विकलांग और बीमार हुए लोग चिकित्सा और राहत की प्रतीक्षा में आये दिन दम तोड़ रहे हैं और संबद्ध अधिकारी-कर्मचारी तथा उनके नजदीकी फर्जी लोग राहत और पुनर्वास की भारी रकम बेरोकटोक लूट रहे हैं! कैसे चल रहा है धंधा?

- *जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भरती कैलाश पवार मारक गैस के दुष्प्रभावों से चार साल तक तिल-तिल कर लड़ता रहा। जब पीड़ा असह्य हो गयी, तो अंततः उसने आत्मदाह कर लिया, ताकि उपचार के लिए चिकित्सकों के समक्ष गिड़गिड़ाने और रोजगार के लिए अफसरों व राजनेताओं के चक्कर लगाने की यंत्रणा से एकमुश्त मुक्ति मिल जाये।*
- *उचित उपचार एवं पुनर्वास की मांग कर रहे गैस-पीडितों के जुलूस में सम्मिलित मोहम्मद इस्माइल ने बल्लभ भवन की देहरी पर दम तोड़ दिया।*
- *शाकिर अली चिकित्सालय के वार्ड नंबर दो में बेड नंबर ३ पर भरती ४५ वर्षीय धर्मस्वरूप सक्सेना छत की ओर टकटकी लगाये ताकता रहता है। वह बरसों से प्रतिदिन एक पैकेट दूध और डबलरोटी की खुराक पर जीवित है। पौष्टिक व पर्याप्त भोजन की उसकी अर्जी गैस राहत मंत्री हसनात सिद्दीकी के यहां लंबित है।*
- *मंगलवारा छावनी में गली नं० ३ मकान नं० ५ में रहनेवाले राशिद खां का दो बार चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। दोनों बार उसे पूर्ण गैस पीड़ित बताया गया। ३१ मई '८६ को उसकी मौत हो गयी। मृत्यु के उपरांत हुए पोस्टमार्टम ने पिछले परीक्षणों की धज्जियां उड़ाते हुए उसे क्षय रोग (टीबी) से पीड़ित बताया। अब उसकी बेवा बानो भी सचिवालय से लेकर गैस राहत मंत्री तक के चक्कर काट रही है। टीबी के शिकार व्यक्ति के परिजनों को गैस राहत के मद का लाभ सरकार भला क्यों दे?*

इस तरह के किस्से और भी हैं। एक भरा-पूरा षड्यंत्र है, जो लगातार पल रहा है। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं जो लाखों लोगों के साथ छल व क्रूर मजाक कर रहे हैं। वे फरियाद कहां करें? सरकार ने भी तो कम रकम पर यूनियन कार्बाइड से समझौता कर कम बड़ा मजाक नहीं किया है?

एक्शन प्लान : मप्र शासन के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने सन ८८-८९ से ९४-९५ तक की अवधि के लिये कार्य योजना तैयार की थी। इसमें गैस पीड़ित क्षेत्रों में नये चिकित्सालय खोलने, कुशल व अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, प्रशिक्षण परिसर की स्थापना, सेवा केंद्र खोलने जैसी अनेक योजनाएं समाविष्ट थीं। पोषणाहार की समस्या को ध्यान मे रखकर एक करोड़ रुपए के व्यय से मुर्गीपालन योजना भी इसमें सम्मिलित थी। इसके तहत ४० हजार मुर्गियां पालने और प्रति वर्ष ९० लाख अंडे संग्रहीत करने का लक्ष्य था। 'संडे हो या मंडे, खाओ अंडे' की तर्ज़ पर बनी इस योजना से प्रत्येक व्यक्ति को सालाना १८० अंडे यानी हर दूसरे रोज एक अंडा मुफ्त देने की योजना थी। यूनियन कार्बाइड से समझौते के बाद यह एक्शन प्लान खटाई में पड़ गया है। इस पर अमल होने के आसार कम हैं।

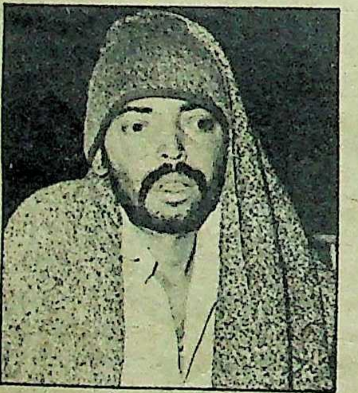

कैलाश पवार

कैलाश पवार मारक गैस के दुष्प्रभावों से चार साल तक तिलतिल कर लड़ता रहा। जब पीड़ा असह्य हो गयी, तो उसने आत्मदाह कर लिया, ताकि अफसरों व राजनेताओं के चक्कर लगाने की यंत्रणा से मुक्ति मिल जाये।

पोषण-आहार ही क्यों, अन्य मोर्चों पर भी अब तक जो कुछ हुआ है, वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। रोगों के निदान के लिये मंहगे उपकरण खरीदे गये, पीड़ितों को 'हरा कार्ड' दिया गया, लेकिन दवाइयां न मिलने की शिकायतें ज्यों-की-त्यों हैं। तालाब में गंदी मछलियों की कमी नहीं है। स्टोरकीपर, अधिकारी और डाक्टर भारी तादाद में दवायें डकार जाते हैं। स्टोरकीपरों के यहां पड़े छापों ने उनके भ्रष्टाचार की कलई बार-बार खोली है। सरकार ने दो चलित चिकित्सालयों की व्यवस्था की है, किंतु इन्हें नियमित रूप से शायद ही किसी वार्ड में देखा गया हो। गैस पीड़ितों के नाम पर सरकार ने लंबा-चौड़ा अमला तैयार कर रखा है, लिहाजा राहत की रकम का बड़ा हिस्सा अमले पर खर्च हो जाता है। यही नहीं, अमला खोटग्रस्त भी है। उसका ध्यान गैस पीड़ितों को राहत पहुंचाने से अधिक अपना हित साधने पर है।

मुआवजा : यह समाज के नैतिक पतन का ही नतीजा है कि वास्तविक गैस पीड़ित दोहरे छल का शिकार हो रहे हैं। अभी तक गैस राहत योजनाओं का लाभ उठाने में वे ही लोग आगे रहे हैं, जो गैस त्रासदी के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन जिनके हाथ लंबे हैं, जो साधन संपन्न हैं और ऊपर पहुंच रखते हैं। क्षतिपूर्ति के दावों को ही लें। इनमें फर्जी दावों की भरमार है। कोई गैस पीड़ित छूट न जाये, इसके लिए सरकार ने जगह-जगह कैंप लगाये थे। मगर इस प्रक्रिया ने गैस पीड़ितों की पहचान ही खत्म कर दी। उन हजारों लोगों ने भी लगे हाथों फार्म भरे, जो या तो तब शहर में थे ही नहीं, या फिर मिक गैस से उनकी बस्तियां अछूती रही थीं। भोपाल के ५६ वार्डों में से ३० वार्डों को गैस प्रभावित निरुपित किया गया था। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में भी राजनीतिक दबावों व प्रभावों का हाथ था, मगर इसे सही भी मान लें, तो इन वार्डों की कुल आबादी

लगभग साढ़े तीन लाख है। रिकार्ड बताते हैं कि अब तक भोपाल के साढ़े छह लाख बाशिंदे दावे का फार्म भर चुके हैं। गैस राहत-तंत्र में ६० प्रतिशत कर्मचारी बाहर के हैं और इनमें से भी करीब ९० प्रतिशत लोगों ने मुआवजे के लिए फार्म भरे हैं। इन कर्मचारियों ने स्वयं को गंभीर गैस पीड़ित घोषित किया है। जाहिर है कि इनमें से बहुतेरों ने संबंध व प्रभाव के बल पर वांछित प्रमाण हासिल कर लिए होंगे। दरअसल, मुआवजे का 'ईजी मनी' कोई छोड़ना नही चाहता। यही कारण है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा लोग क्षतिपूर्ति के दावे कर चुके हैं। अगर वाकई इतने लोग गैस प्रभावित होते, तो पुनर्वास में विलंब, उपचार में अनियमितताओं और यूनियन कार्बाइड के समझौते के विरुद्ध विराट आंदोलन खड़ा हो जाता, लेकिन इनमें से कुछ हजार लोग ही हैं, जो आंदोलन का आवाहन होने पर सड़कों पर निकलते हैं। अब्दुल जब्बार के नेतृत्व में गैस पीडित महिलाओं के मोर्चे को छोड़ दें, तो आज कोई ऐसा जुझारु संगठन नजर नहीं आता, जिसके बैनर तले हजारों गैस पीडित एकत्र हो जायें। अफसोस तो इस बात का है कि गैस त्रासदी के समय राहत कार्य में स्वयं-स्फूर्त हिस्सा लेकर जिन भोपाल के नागरिकों ने मानवीय सेवा की अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत की थी, उन्हीं लोगों ने आज फर्जी दावे भर कर न केवल लाखों गैस पीड़ितों के साथ छल किया है, वरन अपने ही गालों पर तमाचा मारा है। हालांकि, सरकार कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग कर रही है, किंतु उसे धता बताना मुश्किल नहीं है। किसी वास्तविक गैस पीड़ित की एक्सरे रिपोर्ट अपने फार्म के साथ लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकारी तंत्र की खोट और प्रक्रिया की खामियों को उजागर करने के प्रयोजन से 'माया' ने थोड़ा जोखिम उठाया और दो फर्जी नामों से मुआवजे के लिए दावे के फार्म भरे। इन फार्मों को विधिवत जमा कर दिया गया। मजे की बात यह है कि दोनों व्यक्तियों को उनके दिये पतों पर नोटिस भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया गया है। इस मौके पर यदि दो व्यक्तियों को फर्जी मेडिकल रिकार्ड आदि के साथ पेश कर दिया जाये, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन दोनों को मुआवजा मिलने की पूरी संभावना बनती है। स्थिति तो यह है कि इस झंझट से भी बचा जा सकता है। अगर गांठ में पैसे हों और खर्च करने का इरादा, तो स्वास्थ्य परीक्षण की मनचाही रिपोर्ट भी हासिल की जा सकती है। पैसा लेकर गैस पीड़ित होने का प्रमाणपत्र देनेवाले डाक्टर भोपाल में कम नहीं हैं।

धर्मस्वरूप सक्सेना

धर्मस्वरूप सक्सेना
बरसों से प्रतिदिन एक
पैकेट दूध और डबलरोटी की
खुराक पर जीवित है। पौष्टिक व
पर्याप्त भोजन की उसकी अर्जी गैस
राहत मंत्री हसनात सिद्दीकी के यहां
लंबित है।

नया बखेड़ा : गैस त्रासदी के तुरंत बाद जगह-जगह पर अनेक स्वयंसेवी संगठन रातोरात उभर आये थे। अधिकांश ऐसे संगठन वक्त के साथ समाप्त हो गये। जो इनेगिने संगठन शेष हैं, उनमें तीव्र प्रतिद्वंद्विता देखने में आ रही है। ये संगठन एक मंच पर खड़े होने में आज तक विफल रहे हैं। जहरीली गैस कांड संघर्ष मोर्चा के आलोक प्रताप सिंह अनेक संगठनों पर विदेशी साठगांठ का आरोप लगाते हैं, तो गैस पीड़ित महिलाओं के संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार कहते हैं कि उपरोक्त मोर्चे के कर्ताधर्ता अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं और मोर्चे के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आने के मंसूबे बना रहे हैं। दूसरी ओर आलोक प्रताप सिंह ने सतीनाथ सारंगी के साथ विदेश गये १६ वर्षीय सुनील राजपूत, ४० वर्षीय चंदर सिंह और बिलकीस बानो की यात्रा और उसके प्रयोजन पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस टोली ने ब्रिटेन, अमरीका और नीदरलैंड की यात्रा की थी। जब्बार का कथन है कि ये लोग जनमत जागृत करने में सफल रहे, जबकि इन्हें संदिग्ध बताते हुए आलोक कहते हैं कि इन लोगों समेत कुछ अन्य संगठनों की विदेशी पैसे से मदद कर रहे हैं।

फिलहाल भोपाल में गैस पीड़ितों को राहत और उनके हकों के लिये लड़ाई के नाम पर अजीब नजारा दरपेश है। जो वाकई गैस पीड़ित हैं, वे विष दंश झेलने के बाद भी हताश और भौंचक हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनको कब और कितना मुआवजा मिलेगा। 'मिक' ने उनसे काम करने का बूता और औसान छीन लिया है। उनकी स्थिति विकलांग जैसी है, लेकिन उनसे ज्यादा विकलांग है, सरकारी नीति और सरकारी तंत्र। रही सही कसर भोपाल के नागरिकों ने पूरी कर दी है। ऐसे में हजारों गंभीर रूप से विपदाग्रस्त गैस पीड़ितों के समक्ष सिर धुनने के अलावा क्या कोई और विकल्प शेष बचा है?

—एस पी त्रिपाठी

सिंगौली

पुलिस बर्बरता की नयी मिसाल

मंदसौर जिला मुख्यालय से १५० किमी॰ दूर बसे मप्र के सिंगौली कस्बे के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी का असली कारण अधिकारियों की ऐयाशी रही है। इसी के विरोध के कारण गत २० जुलाई को पुलिसवालों ने बर्बरता की सीमा लांघ कर नागरिकों की धुनाई की। पर यह सब हुआ कैसे?

मंदसौर जिले में आठ-दस हजार की आबादी के कस्बे सिंगौली की दूरी जिला मुख्यालय से अधिक है और पड़ोसी प्रदेश राजस्थान से कम। मंदसौर मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किमी दूर बसा यह कस्बा इन दिनों अशांत है। मप्र विद्युत मंडल का नजला सिंगौली पर वर्षों से गिरता आ रहा था, किंतु २० जुलाई '८९ को सिंगौली के राजनीतिक चेतनासंपन्न नागरिकों पर पुलिस बर्बरता की शक्ल में विद्युत मंडल की जो गाज गिरी उसका अहसास आज भी वहां जाने पर सहज हो जाता है। विद्युत मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने जो बर्बरता दिखायी उसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस कदर विचलित व उद्वेलित किया कि उसने इस मुद्दे को लेकर न केवल आंदोलन छेड़ दिया, वरन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुंदरलाल पटवा ने तो आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा तक कर डाली।

पृष्ठभूमि : सिंगौली की त्रासदी की पृष्ठभूमि में दो प्रसंग गुथे हुए मिलते हैं। एक प्रसंग की डोर अवैध संबंधों की कथा से जुड़ी हुई है, तो दूसरी रोज-ब-रोज बिजली कटौती से उत्पन्न क्रोध और सामूहिक खीझ से संबद्ध है। सिंगौली के लोगों का कहना है कि यहां रोजाना बिजली गायब रहती है और अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों पर कभी कान नहीं दिया। "बिजली नीमच से ही गायब है", कहकर लोगों को लड़ाना अधिकारियों की दिनचर्या बन गयी है। इससे कस्बे के लोगों के मन में

बर्बरता के विरुद्ध: सिगौली में पुलिस ज्यादती के बाद कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और अन्य जुलूस के साथ

भीतर-ही-भीतर गुस्सा उफन रहा था। ११ जुलाई की रात को बिजली गुल हो जाने पर स्कूली छात्रों ने मप्र विद्युत मंडल के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। संयोग से इसी दरम्यान दफ्तर में आग लग गयी, जिससे कुछ रिकार्ड व सामान जल गये। बिजली अधिकारियों का कहना है कि आग दुलीचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी छात्रों ने लगायी, जबकि कस्बे के लोग बताते हैं कि आग उस समय लगी, जब जुलूस रास्ते में था। उनका आरोप है कि आग स्वयं बिजली अधिकारियों ने लगायी, ताकि रिकार्डों में की गयी हेराफेरी छुपी रहे। यानी आग लगाकर दोष प्रदर्शनकारियों के मत्थे मढ़ दिया गया। बात यहीं खतम नहीं हुई। अगले ही दिन पुलिस ने दुलीचंद जैन और बीस लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इससे कस्बे में आक्रोश फैल गया और विरोधस्वरूप सिगौली बंद का आह्वान किया गया, जो सफल रहा। दुलीचंद जैन भाजपा की तहसील ईकाई के अध्यक्ष हैं। सफल सिगौली बंद से अधिकारी चेते और जैन को रिहा कर दिया गया। जैन की रिहाई को जनता ने अपनी जीत के रूप में देखा। नतीजतन १८ जुलाई को जैन और रिहा हुए साथियों का जोरदार स्वागत किया गया। रिहाई के बाद बंद का आह्वान वापस ले लिया गया।

हादसा: दुलीचंद जैन की रिहाई के बाद माहौल कुछ शांत हो गया था, किंतु २० जुलाई की घटना ने बुझती हुई आग में घी डालने का काम किया। हुआ यह कि २० जुलाई को प्रातः दस बजे हेड कांस्टेबल रामलाल और भुवनेश बस अड्डे की ओर से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर से एक १२ वर्षीय किशोर श्रीलाल आहत हो गया। इस पर क्रुद्ध भीड़ ने दोनों पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। इनमें से एक पुलिसकर्मी भागकर थाने गया और घटना की सूचना देकर पुलिस बल ले आया। इस पुलिस बल ने आने के बाद आव देखा न ताव, जो सामने आया उसकी पिटाई कर डाली। पुलिस ने घटना से वास्ता न रखनेवाले दुकानदारों को भी नहीं बख्शा और घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्र बर्ताव भी किया। इत्तफाक से उसी वक्त दुलीचंद जैन उपासरा से प्रवचन सुनकर घर लौट रहे थे। पुलिस उन्हें रास्ते से पकड़ कर थाने ले गयी और वहां खुले मैदान में चारों ओर से घेरकर लात, घूंसों व बेतों से बुरी तरह उनको मारा गया। इसी तरह जब भाजपा के वरिष्ठ नेता खुमान सिंह शिवाजी, श्रीलाल बोहरा और देवीसिंह सिंदल नगर में घूमकर घटना की जानकारी हासिल कर रहे थे उस वक्त उन पर पुलिस बल टूट पड़ा था। खुमानसिंह ने किसी तरह एक घर में घुसकर जान बचायी, किंतु और लोग पुलिस की चपेट में आ गये। यही नहीं, ६० वर्षीय मोहनलाल पाराशर इसी कस्बे में रहते हैं, उनके घर में भी घुसकर पुलिस जवानों ने उनकी पत्नी को पीटा और अभद्र आचरण किया। 'माया' ने मंदसौर जेल में बंद दुलीचंद समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की, तो पाया कि उनके शरीर

> जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं, यह आगे की बात है, किंतु फिलहाल भाजपा सिंगौली कांड को मुद्दा बनाकर जनमत जागृत करने और क्षेत्र में चुनावी दृष्टि से अपने पक्ष में हवा बांधने को कटिबद्ध है। हो सकता है कि जांच से किन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई हो, किंतु सिंगौली कांड ने एक बार फिर इस बात पर सोचने को बाध्य किया है कि निर्दोषों को अमानुषिक तरीकों से प्रताड़ित करने की पुलिस की वृत्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाये ?

पर चोटों के निशान अभी भी ताजा हैं। बुरी तरह प्रताड़ित दुलीचंद की चोटों का दर्द अभी भी मिटा नहीं है। कस्बे में कई औरतों ने पुलिस प्रताड़ना की पुष्टि की, किंतु लोकलाज व मर्यादा के भय से उन्होंने नाम न देने का का आग्रह किया।

असलियत : 'माया' ने इस संबंध में खोजबीन के दौरान पाया कि सिंगौली में पिछले दो-तीन माह से जनता और अधिकारियों के बीच अनबन और तनातनी चल रही थी। इसका कारण गांव की एक महिला कैलाश कुंवर से कतिपय प्रशासनिक व एक पुलिस अधिकारी के अवैध संबध थे। गांव की जनता ने इन संबंधों पर कई बार उंगली उठायी और विरोध किया, किंतु इसका तीनों अफसरों पर कोई असर नहीं पड़ा और वे रंगरलियों में लिप्त रहे। १६ जुलाई को अकस्मात कैलाश कुंवर की हत्या हो गयी और उसकी लाश शहर से ३ किमी दूर पायी गयी। कुंवर की हत्या के आरोप में जिस १८ वर्षीय युवक को पुलिस ने बंदी बनाया, वह रिश्ते में मृतक का भाई लगता है। इस घटनाक्रम ने भी कस्बे के लोगों को भीतर-ही-भीतर उद्वेलित किया और उनका क्षोभ २० जुलाई को पुलिस कर्मियों की पिटाई की शक्ल में फूटा, जिसका बदला पुलिस ने अपने तरीके से लिया।

सिंगौली में पुलिस अत्याचार को भाजपा नेतृत्व ने काफी गंभीरता से लिया। कहा तो यहां तक जाता है कि पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सिंगौली को चारों ओर से सील कर दिया था और संचार संपर्कों को भी विच्छिन्न कर दिया था। किंतु घटना की खबर रतलाम के भाजपा विधायक हिम्मत कोठारी को उसी रात लग गयी थी। बकौल कोठारी, उन्होंने उसी रात जिलाधीश धीरज माथुर से संपर्क किया था और अन्याय-अत्याचार रोकने की मांग की थी। किंतु धीरज माथुर ने न तो कोई जवाब ही दिया और न ही कोई कार्यवाही हुई। सुंदरलाल पटवा का कहना है कि कलेक्टर ने सिंगौली आकर पुलिस बल से कहा था, "सत्तर हरामजादों की गिरफ्तारी होनी है।"

दरिंदगी के निशान : घायल प्रेम सिंह परिहार

राजनीतिक यथार्थ : सिंगौली के राजनीतिक यथार्थ पर दृष्टिपात करें, तो यहां भाजपा की जड़ें अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हैं। यह कस्बा विधानसभा के जावद निर्वाचन क्षेत्र में आता है, जहां से वीरेंद्र कुमार सखलेचा चुने जाते रहे हैं। पिछले चुनाव में सहानुभूति लहर में कांग्रेस-इ के चुन्नी लाल धाकड़ यहा से निर्वाचित हुए थे। पुलिस ज्यादती के विरोध में खुमानसिंह शिवाजी, कैलाश चावला और निर्मला भाचावत आदि अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये। घटना के तीसरे दिन सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और बाबू लाल गौर आदि सिंगौली पहुचे और उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से भेंट की। पुलिस बर्बरता के विरोध में मदसौर में भाजपा ने विशाल रैली भी निकाली। भोपाल लौटकर पटवा ने ग्राम कोठरी इस्तमुरार के सरपंच प्रेमसिह परिहार को पत्रकारों के समक्ष पेशकर उसके शरीर की चोटें दिखायीं। सिंगौली में 'माया' से चर्चा में पटवा ने यहां तक कहा कि पुलिस भय से पांच सौ लोग गांव छोड़कर चले गये हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि २७ जुलाई से वे आमरण अनशन पर बैठेंगे।

घटना को लेकर पानी जब सिर से ऊपर जाता दिखा, तो जिला दंडाधिकारी मंदसौर ने मजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये। जांच का दायित्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रघुवीर श्रीवास्तव को सौंपा गया। हालांकि इंका सांसद बालकवि बैरागी ने सिंगौली आने की जहमत गवारा नही की, किंतु पूर्व मुख्यमंत्री सखलेचा ने नीमच में उच्चाधिकारियों से चर्चा की और सिंगौली पहुंचे। सत्तारूढ़ दल ने जब भाजपा को घटना का राजनीतिक लाभ उठाते देखा, तो शासकीय मशीनरी सक्रिय हो उठी। गृहमंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह के निर्देश पर उज्जैन संभाग के आयुक्त आरसी सक्सेना और पुलिस उप महानिरीक्षक २६ जुलाई को सिंगौली पहुंचे।

जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं, यह आगे की बात है, किंतु फिलहाल भाजपा सिंगौली कांड को मुद्दा बनाकर जनमत जागृत करने और क्षेत्र में चुनावी दृष्टि से अपने पक्ष में हवा बांधने को कटिबद्ध है। हो सकता है कि जांच से किन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई हो, किंतु सिंगौली कांड ने एक बार फिर इस बात पर सोचने को बाध्य किया है कि निर्दोषों को अमानुषिक तरीकों से प्रताड़ित करने की पुलिस की वृत्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाये ?

—एसपी त्रिपाठी, सिंगौली से

डा० आरएच रिछारिया

कृषि वैज्ञानिक की उपेक्षा क्यों ?

"एक समय था कि छत्तीसगढ़ में लोकटी-माछी खूब उगती थी मगर बाप-दादाओं के जमाने की इस बेहतरीन प्रजाति को आईआर-८ और रत्ना जैसी बौनी संकर प्रजातियों ने निगल लिया", ७८ वर्षीया डा० आरएच रिछारिया बताते हैं। धान अनुसंधान के इस शलाका-पुरुष ने लगातार सैंतालीस साल खेतों में अध्ययन और अनुसंधान करते हुए गुजारे हैं। आज भी भोपाल से करीब ११ किमी दूर अपने निजी फार्म पर उन्हें काम करते हुए देखना किसी थके-हारे बूढ़े नहीं, वरन युवकोचित उत्साह और समर्पण से सराबोर अध्येता से रूबरू होने जैसा है।

१९४२ से धान अनुसंधान में रत डा० रिछारिया की सेवाएं मप्र सरकार ने पहलेपहल १९७१ में बतौर कृषि सलाहकार ली थीं। इसके पहले वे १९५९ से लेकर १९६७ तक भारत सरकार के कटक स्थित केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे। उन्हें मप्र लाने की पहल तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० श्यामाचरण शुक्ल ने की थी। धान के कटोरे यानी छत्तीसगढ़ से जुड़े शुक्ल बखूबी जानते थे कि डा० रिछारिया की सेवाओं का उपयोग कर छत्तीसगढ़ में धान के खेतों में चमकीली क्रांति लायी जा सकती है। उनकी अध्यक्षता में जब मप्र धान अनुसंधान संस्थान का गठन हुआ, तो वे डा० रिछारिया को उपाध्यक्ष बनाकर संस्थान में ले आयें। जल्द ही उन्हें यह अहसास हुआ कि भोपाल में धान के खेतों से दूर बैठकर मनचीते सपने को साकार नहीं किया जा सकता। परिणामतः १९७२ में संस्थान का मुख्यालय भोपाल से रायपुर ले आया गया और १९७६ में डा० रिछारिया को इस स्वायत्तशासी संस्था का निदेशक बना दिया गया। डा० रिछारिया को सर्वप्रमुख मप्र विशेषकर छत्तीसगढ़ में धान की उपज बढ़ाने और सदियों से प्रचलित देशी प्रजातियों के विकास व उन्नतीकरण का जिम्मा सौंपा गया था।

जर्म प्लाज्म बैंक : हालांकि दायित्व बहुत दुष्कर था, किंतु धुन के पक्के रिछारिया ने जो बीड़ा उठाया था, उसे पूरा कर दिखाया। उनकी अनूठी देन व उपलब्धि थी, जर्म प्लाज्म बैंक। उन्होंने दूर-

दूर तक कस्बों और गांवों की खाक छानी और धान की करीब बीस हजार प्रजातियां एकत्र कीं। इनमें बड़ी संख्या में दुर्लभ व लुप्तप्राय प्रजातियां भी थीं। वस्तुत: गांधीवादी कृषिशास्त्री डा० रिछारिया विदेशी प्रजातियों के अबाध आयात, कीटनाशकों व उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग व स्वदेशी किस्मों की उपेक्षा के विरोधी थे। उम्दा एव विपुल उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील देशी प्रजातियों पर यहां की जलवायु, मिट्टी और पर्यावरण के लिहाज से अजनबी विदेशी प्रजातियों को तरजीह देना उन्हें गवारा न था। यही कारण है कि जब ताइचुंग नेटिव के आयात व इस्तेमाल की बात उठी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। नतीजतन वे डा० स्वामीनाथन के कोपभाजन बने और देखते-ही-देखते विदेशी हितों की पोषक ताकतवर लाबी उनके विरोध में उठ खड़ी हुई।

सचाई यह है कि डा० रिछारिया बरसों से इस लाबी की नजरों में किरकिरी की तरह खटक रहे थे। ७ फरवरी '६३ को आईआरआरआई के सेमीनार में उनके परचे 'क्लोनल प्रोपेगेशन आफ राइस एंड रीसेंट अप्रोचेज टु राइस जेनेटिक्स' ने कृषि वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी थी। अध्ययन व गहन अनुसंधान के बल पर उनकी आधारभूत मान्यता थी कि भारत में धान उत्पादन में विश्व-शक्ति बनने की सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। इस क्रम में चर्चा के दौरान उन्होंने 'माया' से कहा, "भारत में आज भी धान की कुल जमा करीब डेढ़ लाख प्रजातियां मौजूद हैं।" किंतु आयातित एवं संकर वामन प्रजातियां इन्हें शनै:-शनै: निगलती जा रही हैं। दूसरे विदेशी हितों की पोषक शक्तियां भी चाहती हैं और उनकी कोशिश है कि भारत की देशी प्रजातियों का क्षय हो, ताकि भारत आगामी वर्षों में धान के बीजों तक के लिए उनका मोहताज हो जाये।

दुर्भाग्य: १९७७ के चुनावों के बाद मप्र में जनता सरकार आयी, तो उसका नजला धान अनुसंधान संस्थान पर गिरा। डा० रिछारिया के कीमती 'जर्म प्लाज्म बैंक' पर अरसे से मनीला स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्थान की नजर थी। बताते हैं कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अनेक प्रजातियां वहां चली भी गयीं। बहरहाल, १९७८ में डा० रिछारिया को संस्थान के निदेशक पद से हाथ धोना पड़ा। जो काम वे कर रहे थे, वह अधूरा रह गया और बैंक के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे। स्वदेशी प्रजातियों के बल पर धान के खेतों में रजत-क्रांति का सपना अधूरा रह गया। काफी हाथ-पांव मारने के बाद भी जब किसी ने डा० रिछारिया की बातों पर कान नहीं दिया, तो वे मन-मसोस कर रायपुर से भोपाल चले आये और सीमित साधनों के सहारे निजी खेती-बाड़ी और अनुसंधान में लग गये।

इसमें शक नहीं कि देशी प्रजातियों का धीरे-धीरे क्षय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले सुवासित व गुच्छा धान बहुतायत में होता था। अब गुच्छा धान की कुछ ही किस्में शेष हैं। गनीमत है कि मप्र में सुवासित धान की करीब तीन सौ प्रजातियां आज भी हैं। जल्द पकनेवाली सुवासित किस्मों में कदमफूल, लाखो कुंवर, सुकुलमंडी, मध्यम समय में पकनेवाली किस्मों में श्रीमाल और देर से पकनेवाली किस्मों में दुबराज, बादशाह भोग, तुलसी-अमृत, जौफूल, कालीमूछ और चिन्नौर आदि हैं। दुर्लभ प्रजातियों में रायपुर में फिंगेश्वर ब्लाक में दालचीनी, देवभोग, गरियाबंद में महाराजी, बस्तर के अबूझमाड़ में महरी और बिलासपुर के कठघोरा में पदरीरोपा उम्दा प्रजातियां हैं। गुच्छेदार धान की डा० रिछारिया द्वारा संग्रहीत ४८ किस्मों में से कुछ के नाम हैं: आमाझोपा, आमाझे, आमाझूल, खजूरझोपा, मेकराझूल और लहसुन।

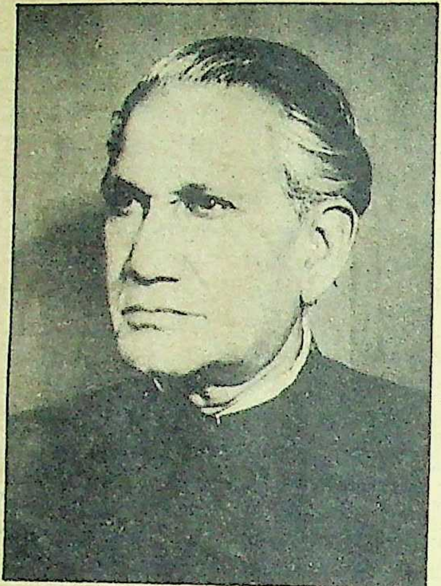

घर का जोगी: डा० आरएच रिछारिया

डा० रिछारिया ने अकेले बस्तर में धान की करीब एक हजार प्रजातिया बटोरी थीं। वे कहते हैं, "धान उत्पादन व अनुसंधान की दृष्टि से बस्तर अत्यंत समृद्ध है। वहां अनेक ऐसी किस्में हैं, जो कम खाद के बावजूद विपुल उत्तपादन में सक्षम हैं। कुछ प्रजातियों में कीड़ों व अन्य रोगों का सामना करने की अद्भुत प्रतिरोधी क्षमता है। डर है कि उधार ली हुई अपाहिज कृषि नीति के चलते ये प्रजातियां कहीं लुप्त न हो जायें।"

भविष्य: डा० रिछारिया का भय अकारण नहीं है। पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि और फिर इंदिरा गांधी कृषि विवि, रायपुर को हस्तांतरित 'जर्म प्लाज्म बैंक' आज न जाने किस हाल में है? डा० रिछारिया की हालत घर का जोगी जोगड़ा जैसी है। उनकी धान उत्पादन की 'क्लोनल प्रोपेगेशन' तकनीक आज फिलिपीन, इंडोनेशिया व मलेशिया में उपयोग में लायी जा रही है, लेकिन भारत सरकार एवं यहां के कृषि पंडितों की नजरों में इसकी कीमत न के बराबर है। कांग्रेस-इ के पुनर्सत्तारोहण के बाद अर्जुन सिह मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने धान अनुसंधान संस्थान को पुनर्जीवित करने पर ध्यान दिया था। उनकी डा० रिछारिया से इस बाबत बातें भी हुई थी, किंतु अर्जुन सिंह कालांतर में सीकरी की गलियों में उलझ गये और बात आयी गयी हो गयी। वोरा मुख्यमंत्री बने, तो एक बार फिर उम्मीद जगी, क्योंकि संस्थान व रिछारिया के कामों से वे व्यक्तिगत तौर पर परिचित थे। मगर लगता है कि संस्थान के पुनर्जीवन में वोरा का आलस्य बाधक बन गया। सबसे बडी विडंबना यह हुई कि सांसद सुभाष यादव की अध्यक्षता में गठित कृषक कल्याण आयोग ने अपनी बृहत सिफारिशों में धान अनुसंधान पर ध्यान देने का कहीं उल्लेख नही किया।

कहावत है, अनहोनी को टालना मुश्किल होता है। धान अनुसंधान के मामले में भी यह बात सही है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डा० रिछारिया के कामों में रुचि ली थी १५ अप्रैल, १९८३ को डा० रिछारिया को इस बारे में एक पत्र भी भेजा गया, जिसमें 'स्पेसिफिक प्लान' तैयार करने को कहा गया था। डा० रिछारिया ने अत्यंत मेहनत से विशेष कार्यकारी योजना तैयार की। पुत्र के उपचार के सिलसिले में उन्हें अचानक इंग्लैंड जाना पड़ गया। वहां से लौटने के बाद उनकी श्रीमती गांधी से बात शुरू हुई, किंतु श्रीमती गांधी की असामयिक हत्या ने डा० रिछारिया की योजना और सपनों को तार-तार कर दिया। डा० रिछारिया का दावा है कि उनकी क्लोनल प्रोपेगेशन तकनीक से धान की किसी भी प्रजाति से उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि उनकी कारगर योजना को अमल में लाया जाये, तो धान उत्पादन को देश में दुगना किया जा सकता है। उनकी योजना पर कसैली, कलकत्ता और पांडिचेरी की स्वयंसेवी संस्थाओं का ध्यान तो गया है, किंतु सरकार का नहीं। इस पकी आयु में भी डा० रिछारिया के मन में काम करने की ललक है। उनमें माद्दा और कूवत भी है। प्रश्न उन्हें दायित्व सौंपने और साधन मुहैया करने का है। यदि राष्ट्रीय चेतना का अभाव न होता, तो देश उन्हें वही सम्मान देता, जो इंग्लैंड ने प्रो० इंगलडाउ को दिया। ढेरों आफरों व प्रलोभनों के बाद भी रिछारिया ने भारत छोड़ने की बात कभी नहीं सोची। डा० रिछारिया के निर्देशन में धान अनुसंधान संस्थान पुनर्जीवित हो जाये, तो अत्युत्तम अन्यथा रायपुर अथवा जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालयों में पृथक पीठ बनाकर शासन उनके अनुभव का लाखों कृषकों के हित में लाभ उठा सकता है। सरकार चाहे, तो उन्हें नेशनल प्रोफेसर बनाकर उनके ऋण से किंचित उऋण हो सकती है। डा० रिछारिया ने 'माया' से कहा, "मैं चाहता हूं कि मेरे पांच दशकों के समृद्ध अनुभव का लाभ देश को मिले।" धान अनुसंधान के इस बूढ़े वैज्ञानिक की यह साध पूरी होगी या अधूरी रह जायेगी, इसका उत्तर देश व प्रदेश के कर्णधारों के अलावा किसी और के पास नहीं है।

—सुधीर सक्सेना

वोट बाजार के नये सौदागर सैयद शहाबुद्दीन

अजनबी नहीं हूं : शहाबुद्दीन

सैयद शहाबुद्दीन खुद अपनी ही बिछायी बिसात में फंस गये हैं। मुस्लिम एव विपक्षी राजनीति के हाशिये में आ चुके सैयद शहाबुद्दीन ने चुनाव वर्ष में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों का नेतृत्व हासिल करने के लिए मुस्लिम सम्मेलन की आड़ में नये राजनीतिक दल के गठन की जो मंशा जाहिर की थी, उससे उनके नजदीकी लोग ही बिदकने लगे हैं और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध दिल्ली में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन में किया।

प्रदेश के अधिकांश मुस्लिम नेता कन्वेंशन के तो पक्षधर हैं, लेकिन उसके लिए किसी और नये दल के गठन के सख्त खिलाफ हैं। जबकि सैयद शहाबुद्दीन का मानना है कि 'मौजूदा समय में कोई भी सियासी पार्टी मुस्लिम समुदाय की हित-संरक्षक नहीं है।' इसलिए एक ऐसे दल के गठन की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका अदा करें, लेकिन इसके साथ ही अन्य समुदायों के लोग भी शामिल हो सकते हों।

जबकि प्रदेश के अधिकांश गैरकट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं का मानना है कि इस नये दल के गठन से उन्हीं शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा, जिनकी मुखालफत सैयद शहाबुद्दीन व अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतें करती रही हैं। इसके उदाहरण के रूप में लोगबाग कांसीराम की पार्टी डीएस-फोर की चर्चा करते हैं।

इन नेताओं का मानना है कि मौजूदा समय में सांप्रदायिकता अपने चरम उन्माद पर है। एक तरफ बाबरी मस्जिद का शोर है, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि की दहाड़ और इनके बीच धर्मनिरपेक्ष ताकतों का सहमा हुआ सन्नाटा है। ऐसे में शहाबुद्दीन द्वारा नये दल का गठन सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती ही देगा, जो न तो मुल्क और न ही कौम के हित में होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता को खुराक देती है। इन नेताओं का कहना था, "सैयद शहाबुद्दीन का नयी पार्टी बनाने का यह कदम हिंदू-मुसलमानों—दोनों के मन में जहर भर देगा। जबकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं का मानना है कि कांग्रेस-इ पार्टी से उनका मोहभंग हो गया है। जनता दल भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि अरुण नेहरू सरीखे नेताओं के चलते जनता दल मुस्लिम हितों का संरक्षक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में शहाबुद्दीन के विचारों के अनुरूप किसी नये दल के गठन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन ये नेता भी सैयद शहाबुद्दीन के इस कदम को संदेह की नजर से देख रहे हैं। इनका कहना है कि एक तरफ तो शहाबुद्दीन मुस्लिम हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर मुस्लिम कन्वेंशन में कई मुस्लिम संगठनों एवं सियासी पार्टियों को शिरकत के लिए बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि इन दलों के नेताओं से उनके मतभेद हैं।

इसके अतिरिक्त जिन दलों एवं संगठनों को बुलाया गया है, वे भी राजनीतिक दल के रूप में अपनी अलग पहचान खोना नहीं चाहते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष कमर काजमी का कहना है कि वोटों की मंडी में मुस्लिम वोट के भाव बढ़ गये हैं। बाजार के इसी रंग को देखकर सैयद शहाबुद्दीन जैसे नये आढ़तिये बाजार में अपनी गद्दी जमाना चाहते हैं।

कमर काजमी तथा अन्य मुसलमान नेताओं को शिकायत है कि शहाबुद्दीन भारतीय मुसलमानों के मतों को बाजारू और बिकाऊ समझते हैं। वे भाव बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं जो मुस्लिम मतदाता और देश की राजनीतिक व्यवस्था दोनों का अपमान है।

—राजेंद्र कुमार

कांग्रेसियों का शिकायतनामा

शिकायतें दूर होंगी : आजाद

दिल्ली दरबार के खास सिपहसालार गुलाम नबी आजाद, इन दिनों राजा मांडा पर काफी आगबबूला हैं। इसी १५ जुलाई को राजा मांडा ने लखनऊ में एक बयान देकर, जब यह कहा कि जवाहर रोजगार और पंचायतराज योजना राजीव सरकार की मृत्यु-पूर्व वसीयत है, तो गुलाम नबी काफी उत्तेजित हो गये। तीन दिनों बाद ही उन्होंने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर राजा के बारे में कहा, "किसी आदमी के लिए इससे बड़ा 'कमीनापन' क्या हो सकता है जो प्रधानमंत्री की मौत और उसकी अंतिम वसीयत की बात करे? वह भी ऐसा आदमी जो राजीव गांधी का मातहत रह चुका हो।"

आजाद के इस कथन पर जब कुछ पत्रकारों ने राजा की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो वे बोले, "गुलामों और नौकरों की बात पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता।"

आजाद द्वारा वीपी को 'कमीना' कहे जाने की जनता दल में भले ही कोई प्रतिक्रिया न हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम इंकाई आज भी गुलाम नबी की 'चोप' वाली झाड़-फटकार से भीतर-ही-भीतर दुखी हैं, जो उन्होंने राजीव गांधी की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से आम कार्यकर्ताओं को पिलायी थी।

इंकाइयों का यह गुस्सा १६ जुलाई की उस बैठक में खुलकर सामने आया जो आजाद की पहल पर चुनाव की पूर्व तैयारी के लिए बुलायी गयी थी। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माल ऐवेन्यू स्थित कार्यालय में बुलायी गयी थी। इस बैठक में प्रदेश इंका के सभी पदाधिकारियों तथा जिले और नगर के इंका अध्यक्षों को ही आमंत्रित किया गया था।

बैठक की कार्यवाही को गोपनीय बनाये रखने के उद्देश्य से उन इंकाइयों को, जो बिना बुलाये बैठक कक्ष में घुस आये थे, जबरन निकाल बाहर कर दिया गया। यहां तक कि मंत्रियों और विभिन्न सेलों के पदाधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी।

हाईकमान के प्रतिनिधि के रूप में गुलाम नबी आजाद और शासन के प्रतिनिधि के रूप में नारायणदत्त तिवारी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश इंका अध्यक्ष बलराम सिंह यादव, अपनी पत्नी के उपचार के सिलसिले में विदेश में होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

बैठक की कार्यवाही आजाद के निर्देश के साथ शुरू हुई। उनके निर्देश थे : (१) सभी जिला अध्यक्ष, अगस्त मास के अंत तक ब्लाक स्तर तक की समितियों का गठन पूरा कर लें। (२) पार्टी के प्रादेशिक पदाधिकारी मुख्यालय (प्रदेश कार्यालय) में उपस्थित रहकर यह देखें कि ब्लाक स्तर तक की समितियों के गठन के बाद प्रत्येक ब्लाक में कम-से-कम चार सार्वजनिक सभाएं अवश्य आयोजित हों। (३) इन सभाओं में जनता की उपस्थिति, सभा में आनेवाले वाहनों, ट्रैक्टरों, ट्रालियों, की विस्तृत रिपोर्ट संभव हो, तो

वीडियो कैसेट के साथ हाईकमान को भेजी जायें। (४) साथ में यह भी बताया जाये कि क्षेत्र के कौन-कौन प्रमुख कांग्रेसी उक्त सभा में आये और कौन अनुपस्थित रहे। (५) इन सभाओं को सफल बनाने में विधायकों, सांसदों, क्षेत्रीय मंत्रियों का पूरा सहयोग लिया जाये। (६) इन सभाओं को सम्पन्न कराने और उनकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने के बाद हाईकमान के अगले आदेश की प्रतीक्षा की जाये।

आजाद के इन निर्देशों के बाद वीपी सिंह और जनता दल के प्रभाव तथा विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों पर गंभीरता से विचार हुआ। तय किया गया कि गांव स्तर तक जवाहर रोजगार योजना और पंचायत राज कार्यक्रम का प्रचार किया जाये। साथ ही वीपी और जनता दल के प्रस्तावित आंदोलनों के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाये।

गुलाम नबी आजाद जब पार्टी के लोगों से विश्वनाथप्रताप सिंह की चुनौती का डटकर और एक होकर सामना करने की बात कह रहे थे, तब उन्हें बताया गया कि जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन से उपजे असंतोष से घर में जो आग लगी है, उसे बुझाये बिना बाहर की चुनौती का सामना कर पाना कठिन है। कई जिलाध्यक्षों ने खुलकर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जहां कांग्रेसियों की उपेक्षा करती है, वहीं इंका के प्रादेशिक पदाधिकारियों ने जिला समितियों के गठन में ईमानदार कांग्रेसियों की उपेक्षा करके घोर मनमानी की है। कई जिलों में तो पैसे लेकर मनमाने लोगों तथा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को पदाधिकारी बना दिया गया है।

आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष चद्रबली ब्रह्मचारी ने तो गुस्से से भरकर कहा कि जिला अध्यक्षों को दुत्कारा जाता है। मुख्यमंत्री से मिलने जाने पर मुख्यमंत्री के चपरासी और चौकीदार ही हमें कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा देते हैं। ज्यादातर मंत्री लखनऊ के बजाय दिल्ली में डेरा डाले पड़े रहते हैं। विकास कार्यों के लिए तो पैसा न होने की शिकायत की जाती है, फिर यह देखने-पूछनेवाला कोई नहीं कि दिल्ली में बैठकर प्रदेश के मंत्री लाखों रुपए भोजन भत्ते में क्यों फूक रहे हैं? आजमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री सुशीला रोहतगी ने २० सूत्रीय कार्यक्रम की आज तक एक भी बैठक नहीं बुलायी।

आगरा के एक इंका पदाधिकारी ने आधा दर्जन मंत्रियों के नाम लेकर कहा, "ये सभी इतने भ्रष्ट हो गये हैं कि दोनों हाथों से पैसा बटोरने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है।" स्वास्थ्य मंत्री गोपीनाथ दीक्षित, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अम्मार रिजवी, सिचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी, पशुपालन मंत्री अरुण कुमार सिह मुन्ना, नगर विकास मंत्री बलदेव सिह आर्य और ग्राम्य विकास मंत्री श्याम सूरतउपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाये गये।

अलीगढ़ के पदाधिकारी ने पार्टी में जाट वर्ग के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के एक मंत्री महेंद्र सिह टिकैत को समर्थन दे रहे हैं। मुजफ्फर नगर में यही मंत्री पार्टी में जमकर गुटबाजी कर रहे हैं।

वाराणसी की जिला अध्यक्ष चंद्रा त्रिपाठी की शिकायत थी कि वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी में एक भी हरिजन नहीं रखा गया। गाजीपुर के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यकों की उपेक्षा से दुखी थे। बरेली के जिला अध्यक्ष की शिकायत थी कि ऐसा जान पड़ता है कि बनियों के अतिरिक्त जिले में और कोई कांग्रेस का नाम लेनेवाला नहीं। नैनीताल के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सब कुछ नारायणदत्त तिवारी की मर्जी से होता है। वे जिसे उठायेंगे, वही उठेगा, जिसे बिठायेंगे वही बैठेगा। झांसी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इसलिए आपे से बाहर थे कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रणजीत सिंह जूदेव ने सब अपने चहेतों को जिला कमेटी में भर दिया है, जिनमें ज्यादातर अपराधी हैं।

ललितपुर जिला कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि उसे तो जैसे सांसद सुजान सिह बुंदेला ने अपनी रखैल बना लिया है। हरिद्वार, देवरिया, अलीगढ़, जौनपुर, बुलंदशहर और शाहजहांपुर के जिला अध्यक्षों ने जिला समिति के गठन पर गहरा असंतोष प्रकट किया। प्रायः सबने कहा कि जिला कमेटी के गठन से पूर्व हमें आश्वस्त किया गया था कि साठ प्रतिशत नियुक्तियां हमारी सस्तुति पर की जायेंगी। पर बाद में हमें अंगूठा दिखा दिया गया।

बैठक में सुलगी इस आग और धुएं से गुलाम नबी आजाद को यह समझने में कठिनाई न हुई कि घर के हर कोने और कोठारे में आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए उन्होंने कहा कि यह चुनाव वर्ष है और घर की लड़ाई खतरनाक हो सकती है। यह समय लड़ने-झगड़ने का नहीं। आग पर पानी डालते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, "ठीक है, आप लोग जिले के चार-चार नाम दे दें। आप जो नाम देंगे उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी के ओहदेदारों में शामिल कर लिया जायेगा।" जिला अध्यक्षों के अहं की तुष्टि के लिए ऐसे संकेत दिये गये कि आगे से उनकी राय की कद्र की जायेगी। ठीक भी था, यदि बातों से आग बुझ जाये, तो इसमें दरिद्रता क्यों दिखायी जाये?

हिस्ट्रीशीटर नेता की चाह

बाराबंकी के पंच किसान सम्मेलन में न तो किसानों के हित के नारे लग रहे थे और न इंदिरा गांधी-राजीव गांधी का जय-जयकार हो रहा था। वहां तो बस यही नारे लग रहे थे—'रंजीत बहादुर जिन्दाबाद,' 'हमारा नेता कैसा हो, रंजीत बहादुर जैसा हो'।

यह रंजीत बहादुर श्रीवास्तव कौन हैं? लखनऊ और बाराबंकी में वे ४० आपराधिक मामलों से सम्बद्ध रहे। आतकवाद विरोधी अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनका चालान हो चुका है। गत अप्रैल मास में ही वे जेल से छूटे हैं।

रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बाराबंकी के कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र नाथ अवस्थी उर्फ पुत्तू अवस्थी से सम्बद्ध हैं। पिछले वर्ष के अंत में विधायक पुत्तू अवस्थी ने रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को कांग्रेस में शामिल कराया था। एक सार्वजनिक आयोजन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बलराम सिह यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया। रंजीत बहादुर ने, कहा जाता है कि, प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिह यादव को २१ हजार रुपए की थैली भेंट की और बलराम सिह ने रंजीत बहादुर को कांग्रेस में शामिल करने के साथ उन्हें बाराबंकी व्यापारी प्रकोष्ठ का महामंत्री नियुक्त किया। चर्चा थी कि रंजीत बहादुर ने थैली के लिए ५१ हजार रुपए एकत्र किये थे।

रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के क्रियाकलाप सामने आने पर प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिह यादव को परेशानी हुई थी।

विधायक सुरेंद्र नाथ अवस्थी उर्फ पुत्तू अवस्थी ने ताजा आयोजन में केंद्रीय राज्यमंत्री राजेश पायलट, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री अरुण सिह मुन्ना, खाद्यमंत्री हुकुम सिह, परिवहन राज्यमंत्री प्रमोद तिवारी आदि के साथ रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को मंच पर बैठाया। इस किसान सम्मेलन में बाराबंकी के और भी कई ज्ञात अपराधकर्मी मौजूद थे।

सम्मेलन से पूर्व रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की वीडियो फिल्म तैयार की गयी। सम्मेलन में भी रंजीत बहादुर के नारे लगे। रंजीत बहादुर ने राजेश पायलट को माला पहनायी और

रंजीत बहादुर ने, कहा जाता है कि,
प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिंह यादव को २१ हजार रुपए की थैली भेंट
की और बलराम सिंह ने रंजीत बहादुर को कांग्रेस
में शामिल करने के साथ उन्हें बाराबंकी व्यापारी प्रकोष्ठ का
महामंत्री नियुक्त किया।

सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के लिए आवश्यक धन भी रंजीत बहादुर ने एकत्र किया था।

सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक उमाशंकर मौजूद थे, जब उनसे पूछा गया कि 'क' श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर रंजीत कुमार इस आयोजन का कर्ताधर्ता कैसे बना और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से क्या यह आवश्यक नहीं था कि सरकार को इसकी सूचना दी जाती? तब पुलिस अधीक्षक उमाशंकर का कहना था, "मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। राजनीतिक दल सम्मेलन करते हैं। उसके आयोजक कैसे व्यक्ति हैं यह जानना या इसकी सूचना सरकार को देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।"

पुलिस अधीक्षक उमाशंकर का यह उत्तर गोरखपुर की उस घटना से कितना भिन्न है, जिसमें तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक दयाशंकर भटनागर ने हरिशंकर तिवारी को श्रीमती गांधी के पास फटकने तक नहीं दिया था। दोनों घटनाएं राजनीति में अपराधियों के न केवल बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि यह संकेत भी करती हैं कि पुलिस ने अब 'मूंदहु आंख कतहुं कछु नाहीं' की भंगिमा अपना ली है।

—रामपाल सिंह

महाराष्ट्र

भाजपा और शिवसेना की साठगांठ क्या रंग लायेगी?

भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में चुनावी तालमेल को भाजपा के महासचिव प्रमोद महाजन की निजी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। भाजपा की बंबई शाखा के अध्यक्ष हशु आडवाणी शुरू से ही शिवसेना से दोस्ती के खिलाफ थे। इसके बावजूद बंबई महापौर चुनाव में प्रमोद महाजन ने पार्टी का समग्र वोट न केवल शिवसेना को देनें का निर्देश दिया था, बल्कि खुद मतदान के वक्त हाजिर रहकर निगरानी भी करते रहे।

अनुभूत सत्य: महाजन जैसे नेता चुनावी अनुभवों से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे वोट तो शिवसेना की ही झोली में जायेंगे। इसलिए भाजपा की महाराष्ट्र शाखा ने चालू वर्ष के शुरू में समझौते की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव भेजा। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा की महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष गोपीनाथ मुंडे ने की। महाजन और मुंडे का साला-जीजा का नाता है।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह अंदेशा सताता रहा है कि महाराष्ट्र में हुए समझौते का बाकी राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि महीनों फैसला टलता रहा। बाद में महाराष्ट्र शाखा व प्रमोद महाजन की बात इसलिए मानी गयी, क्योंकि केंद्रीय नेताओं को लालच दिया गया कि समझौते की बदौलत राज्य में चार-पांच सांसद चुनकर आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में जनसंघ या भाजपा को लोकसभा में इतने स्थान आज तक नहीं मिले।

बाजी मेरे हाथ: ठाकरे

यों पार्टी सचिव प्रमोद समझौते के पक्ष में यही तर्क देते हैं कि गैरकांग्रेसी वोट बंटना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि गत पांच वर्षों में शिवसेना विपक्ष की महत्वपूर्ण ताकत बनी है। भाजपा को गत वर्ष औरंगाबाद महानगर पालिका की करारी हार अभी भी याद है। ६० स्थानों पर उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद भाजपा को एक भी जगह नहीं मिली थी। शिवसेना ने तो अपने महापौर तक बना लिये—औरंगाबाद, बंबई तथा कई अन्य जिलों में भी।

चुनाव का समीकरण: इस साठगांठ का एक सबब यह भी बताया जाता है कि फिलहाल शिवसेना की नजर महाराष्ट्र विधानसभा पर है। उसकी लोकसभा में दिलचस्पी नहीं है। यों शिवसेना के महत्वपूर्ण सूत्रों ने 'माया' को बताया, "लोकसभा के आठ स्थानों पर सेना के उम्मीदवार खड़े किये जायेंगे। २० सीटें भाजपा के लिए छोड़ी जायेंगी।" यहीं तालमेल में दिक्कत आ सकती है। बंबई में दो, ठाणे व रायगढ़ (अलीबाग), औरंगाबाद, नासिक, अकोला तथा जालना में शिवसेना लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ठाणे, नासिक तथा बंबई पर भाजपा की भी नजर है। कहा तो यहां तक जाता है कि प्रमोद महाजन खुद शिवसेना की मदद से बंबई ईशान्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी क्षेत्र से युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख गुरुदास कामत चुने गये थे, जिनकी हालत इन दिनों पतली है। १९७७ के आमचुनाव में भाजपा (तब जनता पार्टी में समाहित) के राम जेठमलानी तथा वसंत पंडित लोकसभा में चुनकर गये थे।

> **कुल मिलाकर एक बात साफ हो गयी है, नये चुनावी समीकरण से अगले आम चुनाव में कांग्रेस का टिकना बहुत मुश्किल हो गया है।**

यों भाजपा का इरादा राजापुर में भी उम्मीदवार खड़े करने का है, किंतु एक गुप्त सूचना के अनुसार वहां के प्रतिनिधि व जनता दल नेता मधु दंडवते ने बाल ठाकरे से बात की थी और ठाकरे ने उन्हें मदद का अभय दान दे दिया है। ऐसे में इस सीट के लिए भी भाजपा-शिवसेना के बीच तू-तू, मैं-मैं मच सकती है।

इंका की परेशानी: इन दोनों के गंठजोड़ के कारण जनता दल की महाराष्ट्र शाखा तथा राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य में भाजपा से तालमेल न करने का निश्चय किया है। इसके बावजूद जद की महाराष्ट्र शाखा की अध्यक्ष मृणाल गोरे ने कहा है कि तिरंगी लड़ाई रोकने के प्रयत्न होंगे। यानी लोकसभा के जिन स्थानों पर भाजपा का दावा तथा प्रभाव है, वहां राष्ट्रीय मोर्चा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा।

भाजपा में एक वर्ग ऐसा भी है, जो मानता है कि लहर जनता दल तथा वीपी सिंह की है, इसलिए कामचलाऊ सहयोग जरूर होना चाहिए। १८ जून '८९ को बंबई में भाजपा नेताओं की बैठक में अध्यक्ष मुंडे ने जनता दल के फैसले पर दुख प्रकट किया और कहा, "हम पहल करेंगे तथा तालमेल के लिए अनुरोध करेंगे, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू आना कठिन भी तो हैं!"

कुल मिलाकर एक बात साफ हो गयी है, नये चुनावी समीकरण से अगले आम चुनाव में कांग्रेस का टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। संभवत: इस खतरे को भांपने से ही इंका की चिंता बढ़ी है। शिवसेना से मुकाबले का वायदा कर मुख्यमंत्री शरद पवार ने जिला परिषदों तथा नगर परिषद, महानगर पालिकाओं के चुनाव सितंबर '९० तक टाल दिये हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि उन्हें पराजय का भय खाये जा रहा है।

वैसे भी इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित युवकों की प्रचार-मशीनरी तथा शिवसेना के उग्र कार्यकर्ताओं का दबदबा चुनाव पर असर डालेगा। भाजपा के व्यापारी तथा ब्राह्मण समर्थक शिवसेना का चंदा वसूलने वाले नेताओं से नाखुश सही, परंतु दोनों मिलकर काम करेंगे। जातीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते। हां, तिकोना संघर्ष होने से कुछ जगह कांग्रेस को फायदा जरूर मिल सकता है। पिछले हर चुनाव-विश्लेषण से यही साबित हुआ है।

—बंबई ब्यूरो

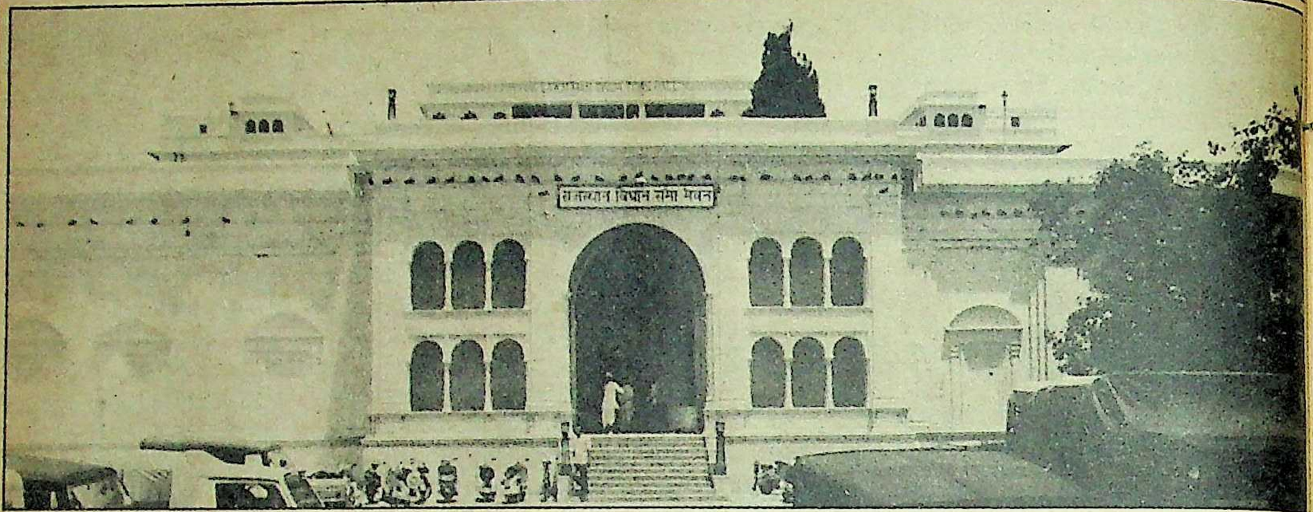

अलग संवैधानिक पहचान : राजस्थान विधानसभा भवन

छाया : प्रताप सिंह

विधानसभा में व्यक्ति-स्वातंत्र्य के नमूने

देश की किसी भी विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप चर्चा के विषय बनते हैं, पर राजस्थान विधानसभा संभवत: देश की पहली विधानसभा है, जहां सदस्य संविधान के पालन के लिए ली गयी शपथ को भी झुठलाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। राज्य विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने ऐसा ही एक दृश्य पेश किया है। राज्य में यह चर्चा काफी गर्म है कि गत १० जुलाई को जब विधानसभा में सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा और आरएसएस पर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के आरोप लग रहे थे, तभी भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने गर्व से घोषणा की, "मैं सांप्रदायिक हूं, कट्टर ब्राह्मण हूं और सांप्रदायिक रहूंगा तथा सांप्रदायिकता में विश्वास करता हूं।" गजब तो यह है कि सदन में तिवाड़ी के इस बयान पर किसी को एतराज नहीं हुआ। आसन (विधानसभा अध्यक्ष) ने इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, यानी मान लिया गया कि व्यक्ति की अपनी आजादी किसी भी शपथ अथवा अनुशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री पर आरोप : इसी पावस सत्र में विपक्ष के नेताओं ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर आरोप इस अंदाज से लगाये कि संबंधित मंत्री को भंडाफोड़ होने का भय लगे और भंडाफोड़ भी न हो। मसलन खनिज एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी, नाथू सिंह और शिवचरण सिंह ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि खुद मुख्यमंत्री बेनामी खान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने इस आरोप पर चुनौती देते हुए कहा, "मेरे नाम से एक भी खान या जमीन का ऐसा टुकड़ा होना सिद्ध कर दें, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।"

लक्ष्मण सिंह

लक्ष्मण सिंह का कहना था, "माननीय विधायक (कु० जैन) के लिए कई बातें ऐसी कही जाती हैं, जिनको सुनकर शर्म से सिर नीचा हो जाता है, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते।"

माथुर की इस चुनौती के जवाब में भाजपा विधायक नाथू सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र मांडलगढ़ के बिजौलिया क्षेत्र में, बिजौलिया सहकारी समिति के नाम से होनेवाला खनन कार्य स्वयं मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। मुख्यमत्री का इस आरोप से इनकार स्वाभाविक था। इस पर घनश्याम तिवाडी का आरोप था कि सहकारी समितियों को आवंटित खानों के कुल क्षेत्र को समिति के सदस्यों के नाम करने का आदेश जारी कर मुख्यमंत्री ने अपने चहेते पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह तथा हाफिज मोहम्मद व तेजाबुल गाग को लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री के पुन: इनकार पर तिवाड़ी ने तमक कर कहा, "मेरे पास अपने आरोपों के प्रमाण हैं।" उनका दावा था कि आरोप गलत हुए, तो वे सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल सदन में सारा मामला आरोपों तक सीमित रहा। पता नहीं किस उद्देश्य से भाजपा के नेताओं ने वे प्रमाण सदन के पटल पर नहीं रखे जिससे उनके आरोप हकीकत में बदल सकें।

जगमाल सिंह बनाम जाखड़ : आरोपों की इस झड़ी में एक आरोप लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ पर अलवर जिले की तिजारा तहसील के

कुछ गांवों में बेनामी जमीनें आवंटित कराने को लेकर लगा। जनता दल के विधायक जगत सिंह दायमा व भाजपा के नाथ सिंह ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये आरोप लगाया था, जाखड़ ने ३१२ बीघा १८ बिस्वा कुल आवंटित भूमि में से ९८ बीघा भूमि को बेनामी ढंग से ग्यारह लोगों के नाम आवंटित करवा लिया है। जाहिर है, सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कह सकी। ऐसे में जनता दल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं विधायक नाथूराम मिर्धा से चुप नहीं बैठा गया। जातीय रिश्ते से बंधे मिर्धा ने विपक्ष के शोर-शराबे को रोकते हुए कहा, "जिस मामले में बहुत ऊंची कुरसी का नाम जुड़ा हो, उसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। लोग बलरामजी को चरखी बना रहे हैं। बलरामजी की यों खिंचाई होती रहे, यह ठीक नहीं है। सरकार पूरी सक्षम है, उसे तुरंत वास्तविकता से सदन को अवगत करा देना चाहिए।" बस मामला कुछ घंटों की हाय-हाय के साथ जहां का तहां रह गया। इस प्रकरण में दिलचस्प बात यह रही कि तिजारा क्षेत्र से निर्वाचित जनता दल के विधायक जगमाल सिंह यादव ने मामला सदन में उठने से पहले ही १३ जुलाई को उसे प्रेस के सामने रख दिया। उन्हें उम्मीद थी कि १४ जुलाई को जब अखबार प्रकाशित होंगे, तो सदन के जागरूक सदस्य तुरंत सरकार से सवाल करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, यहां तक कि जनता दल के सदस्यों ने भी इस पर गौर नहीं किया। मजबूरन यादव को-अपने सवाल में दम पैदा करने के लिए अपने दल के विधायक दायमा के अतिरिक्त भाजपा का सहयोग लेना पड़ा और वह भी अपने ही दल के अध्यक्ष के हस्तक्षेप से कमजोर पड़ गया। ऐसा होने के पीछे क्या कारण थे, यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बेनामी आवंटन की कथा जरूर उजागर हो गयी। वैसे जगमाल सिंह उन विधायकों में से हैं, जिन्हें जनता दल के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा पसंद नहीं करते।

नाथू सिंह

विधायक नाथू सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र माडलगढ़ के बिजौलिया क्षेत्र में, बिजौलिया सहकारी समिति के नाम से होनेवाला खनन कार्य स्वयं मुख्यमंत्री करवा रहे हैं।

विधायक जगमाल सिंह यादव के अनुसार तिजारा क्षेत्र में ९८ बीघा १३ बिस्वा जमीन का बेनामी आवंटन ग्यारह लोगों के नाम जून '८९ में हुआ। वे बताते हैं कि यह जमीन तिजारा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत महसरा के ग्राम खुशकड़ा में आवंटित की गयी है। खुशकड़ा हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। १५ जून को 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान के तहत इस क्षेत्र में राजस्व शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर के दौरान ग्यारह लोगों—घन सिंह पुत्र किशोरी जाट को खसरा नंबर १४० की आठ बीघा, मंजीत पुत्र जागीराम जाट को खसरा नंबर १४१ की नौ बीघा नौ बिस्वा, राजेंद्र पुत्र अमींद जाट को खसरा नंबर ११९ की आठ बीघा नौ बिस्वा, पदम सिंह पुत्र रामपत जाट को खसरा नंबर ३२६ की सवा तीन बीघा, भूप सिंह गुर्जर पुत्र भूलेराम गुर्जर को खसरा नंबर १४० की आठ बीघा, मनीराम शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा को खसरा नंबर १३९ की नौ बीघा तथा लक्ष्मी नारायण पुत्र रामनिवास महाजन को खसरा नंबर १३९ की पांच बीघा जमीन आवंटित की गयी है। विधायक जगमाल सिंह का आरोप है कि ये सब नाम फर्जी हैं और जमीन वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड को आवंटित की गयी है। यादव के अनुसार सभी आवंटियों ने अपने को भिवाड़ी गांव का निवासी बताया है, जबकि तहकीकात करने पर पता चला कि उक्त नामों के लोग वहां हैं ही नहीं। यादव ने मई '८९ में तैयार हुई भिवाड़ी की मतदाता सूची को जांचा और पाया कि वहां भी आवंटियों के नाम दर्ज नहीं हैं। इसी प्रकार तिजारा पंचायत समिति के राशन कार्डवाले यूनिट रजिस्टर में ये नाम नदारद हैं। उनके अनुसार ग्यारह आवंटियों में से सात लोग जाट जाति के हैं, जबकि भिवाड़ी गांव में एक भी जाट परिवार नहीं है।

नोकझोंक की नौटंकी: उक्त तथ्यों के बावजूद सत्ताधारी दल का खामोश रहना तो समझ में आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करनेवाले विपक्षी दलों का कसमसा के चुप रह जाना किसी की समझ में नहीं आता। आरोप की स्वतंत्रता के इस माहौल में नतीजेवाला विवाद केवल एक ही हुआ। दस जुलाई को पूर्व गृह राज्यमंत्री लक्ष्मण सिंह पर भाजपा की कुमारी पुष्पा जैन ने आरोप लगाया कि भीलवाड़ा के एक कुख्यात व्यक्ति से पूर्व गृहमंत्री का संबंध है। यह संबंध समाचारपत्र में छपी एक फोटो के आधार पर स्थापित किया गया, जिसमें कुख्यात व्यक्ति पूर्व मंत्री को साफा पहना रहा है। इस पर पूर्व गृहमंत्री ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा, "मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि समाचारपत्र में आयी हुई किसी बात को उचित मानकर अगर वे आरोप लगाती हैं, तो क्या हम भी उसी आधार पर आरोप लगा सकते हैं?" उनका कहना था, "माननीय विधायक (कु० जैन) के लिए कई बातें ऐसी कही जाती हैं, जिनको सुनकर शर्म से सिर नीचा हो जाता है, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते।" लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता भैरोंसिंह सभापति के कक्ष में गये और बाद में बताया गया कि दोनों सदस्यों के 'विशेष संवाद' विधानसभा की कार्यवाही से निकाल दिये गये, जबकि सदन की अधिकृत कार्यवाही में वे आज भी दर्ज हैं।

जन प्रतिनिधियों के अपने विशेषाधिकारों के कारण वे तथ्य जनता के सामने आने से रह गये, जिनसे उनके सिर नीचे होते हैं। बहरहाल, पूर्व गृह एवं खान राज्यमंत्री को भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने खान आवंटन के मामले में पुनः लपेटा। इस बार लक्ष्मण सिंह ने सभापति को अपना सशर्त इस्तीफा पेश किया और घनश्याम तिवाड़ी को चुनौती दी कि वे अपने आरोप साबित करें, तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाये अन्यथा तिवाड़ी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़-बढ़ कर चुनौती देनेवाले भाजपा विधायक के लिए यह नया अनुभव था। उन्होंने अपने नेता से राय ली और दो घंटे बाद न्यायिक जांच की शर्त के साथ अपना इस्तीफा सशर्त सभापति को सौंप दिया।

घनश्याम तिवाड़ी

विधायक घनश्याम-तिवाड़ी ने गर्व से घोषणा की, "मैं सांप्रदायिक हूं, कट्टर ब्राह्मण हूं और सांप्रदायिक रहूंगा तथा सांप्रदायिकता में विश्वास करता हूं।"

विधानसभा के सत्र के समापन के बाद इन चुनौतियों और घोषणाओं का क्या अर्थ रह जायेगा, यह तो वक्त ही बतायेगा। बहरहाल यह सच है कि राजस्थान विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में जो कुछ देखने-सुनने को मिला, वह किसी रंगमंचीय नोंकझोंक से ज्यादा असरदार नहीं था।

—ओम सैनी

इस्तीफा प्रकरण

ढाई दिन का संकट

हरियाणा में मंत्रियों के इस्तीफे का वह रहस्यमय प्रकरण, जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विपक्ष को ६० घंटे तक दुश्चिंता और बेचैनी में फांसे रहा, वस्तुतः क्या था और कैसे समाप्त हुआ ?

इस्तीफा देना, इस्तीफे लेना और जब चाहा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना चौधरी देवीलाल के लिए कोई नयी बात नहीं। लेकिन जब भी वे ऐसा करते हैं, उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि वे अपने दल के एकछत्र नेता हैं।

यही निष्कर्ष है उस इस्तीफा-प्रकरण का जो शुक्रवार, २८ जुलाई से शुरू हुआ और रविवार, ३० जुलाई के अपराह्ण तक जारी रहा। लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि धर्मवीर सिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होनेवाले मंत्रियों के चौधरी देवीलाल इस्तीफे मांगने जैसा सख्त कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे कृषि मंत्री रणजीत सिंह सहित छह मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर सबको दंग कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में बैठे जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक हतप्रभ रह गये। ये नेता टेलीफोन पर चौधरी देवीलाल से संपर्क न हो पाने के कारण बहुत बेचैन थे और जब उन्हें पता चला कि रविवार की शाम पांच बजे चौधरी देवीलाल, राज्यपाल हरिआनंद बरारी से मिलने जा रहे हैं, तो शीर्ष नेता वाकई चिंतित हो उठे। उन्होंने चंडीगढ़ आकर चौधरी देवीलाल को समझाने की सोची, लेकिन जब तक विश्वनाथप्रताप सिंह, शरद यादव तथा जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी चंडीगढ़ पहुंचे, तब तक अंत भला सो भला की तर्ज पर सारा विवाद हल हो चुका था तथा विवाद को हल कराने का श्रेय भी देवीलाल मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सहयोगी—वीरेंद्र सिंह तथा डाक्टर किस्पाराम पूनिया ले उड़े थे। दिल्ली से आये नेताओं ने रस्मी बातचीत की, रात में पिंजौर में दावत खायी और सुबह दिल्ली लौट आये। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चौधरी देवीलाल को अपने बड़े बेटे ओमप्रकाश चौटाला की सूझबूझ पर ज्यादा भरोसा है। चौटाला की जीवन शैली पर चौधरी देवीलाल की देहाती जीवन शैली की छाप है और उनका अपना जनाधार है, जबकि रणजीत सिंह ठीक इसके उलटे हैं। इसलिए देवीलाल ने हरियाणा जनता दल अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला के सुझाव पर धर्मवीर सिंह को पुनः मंत्रिमंडल में लेना स्वीकार कर लिया था।

उल्लेखनीय है कि जून १९८७ के विधानसभा चुनाव में तोशाम (भिवानी जिला) निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल को हराने के पुरस्कारस्वरूप चौधरी देवीलाल ने धर्मवीर को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, लेकिन गत दो जून को उनके विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को मंजूर करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न केवल उनका चुनाव रद्द किया, वरन् छह वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया।

इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्थगन आदेश न मिलने पर गत पांच जून को धर्मवीर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में चले गये। वहां से गत २५ जुलाई को उन्हें हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अंतरिम निर्णय में स्थगन आदेश प्राप्त हो गया। उसी दिन से चर्चा गरम थी कि धर्मवीर दुबारा मंत्रिमंडल में आयेंगे। भिवानी में तो यह चर्चा थी कि २७ जुलाई को ही वे मंत्रिपद की शपथ ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को राजी करने में २८ जुलाई हो गयी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री को यह समझाया गया कि धर्मवीर को भिवानी लोकसभा सीट पर चौधरी बंसीलाल के विरुद्ध चुनाव लड़ाया जाये और इसके लिए उन्हें मंत्री बनाकर ताकत देनी जरूरी है।

हैसियत की नुमाइश : चौधरी देवीलाल

कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस स्थगन के सहारे धर्मवीर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, यह तो विधिवेत्ताओं की बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेने का रणजीत सिंह और उनके गुट द्वारा विरोध किया गया। चौधरी देवीलाल को बताया गया कि देशभर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अदालत द्वारा अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति को दुबारा मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। चौधरी देवीलाल को यह भी बताया गया कि धर्मवीर चुनाव तो लड़ नहीं पायेंगे, लेकिन इससे सरकार की छवि पर अवश्य आंच आ जायेगी।

चौधरी देवीलाल ने इस विरोध को सुना अनसुना कर दिया। उधर राज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की कि जब तक वे सुप्रीमकोर्ट का अंतरिम आदेश नहीं देख लेते, तब तक धर्मवीर को मंत्रिमंडल में लेने की सिफारिश नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल २८ जुलाई की सुबह दिल्ली से उक्त आदेश को लेकर चंडीगढ़ आये और सीधे राज्यपाल के पास चले गये। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने तक दस बज गये, अतः शपथग्रहण का समय १२ बजे का रखा गया। दो घंटे में सबको लिखित आमंत्रण पहुंचाना असंभव था, अतः फोन पर संपर्क शुरू हो गये और इन संपर्कों का नतीजा यह हुआ कि समारोह में जनता दल के एक ही मंत्री पहुंचा और वे भी चौटाला गुट का प्रमुख स्तंभ गृहमंत्री सम्पत सिंह। भाजपा के तीन-चार मंत्री अवश्य आ गये।

मुख्यमंत्री को आभास हुआ कि रणजीत गुट ने विरोध प्रकट करने के लिए इस समारोह का बहिष्कार किया। राजभवन से अपने कार्यालय आते ही उन्होंने अपने स्टाफ से उन मंत्रियों की सूची लाने को कहा जो शहर में होते हुए भी शपथग्रहण समारोह में नहीं आये। रणजीत सिंह सहित ऐसे छह मंत्री निकले। उनके इस्तीफे टाइप कराये गये और फिर एक-एक करके छहों को इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया।

इन सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जान-बूझकर ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में उन्हें समारोह के समय की पूर्व सूचना ही नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि फिर भाजपा के चार मंत्री कैसे पहुंच गये ? यह बात बाद में जांच से स्पष्ट हुई कि भाजपा की श्रीमती सुषमा स्वराज (शिक्षामंत्री) को समय की जानकारी थी और उन्होंने अपने साथी मंत्रियों को सूचित कर दिया था। भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री राजस्वमंत्री सूरजभान ने भी मुख्यमंत्री को बताया कि औपचारिक रूप से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी। वे तो श्रीमती स्वराज के कहने पर समारोह में पहुंच गये।

चौधरी देवीलाल शुक्रवार की शाम को इस्तीफे अनिर्णीत छोड़कर सबको संशय की स्थिति में डालकर चंडीगढ़ लगभग पचास किलोमीटर दूर हरियाणा के एकमात्र पर्वतीय पर्यटनस्थल मोरनी जा बैठे। इस प्रकार से उनका अन्य स्थानों से संपर्क जाता रहा, क्योंकि वहां फोन की सुविधा नहीं है। दिल्ली के नेता इस संकट पर उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन संपर्क न हो पाने के कारण बेचैन थे। दिल्ली में बैठे जनता दल और भाजपा के शीर्ष नेताओं को लग रहा था कि इस संकट का असर समूचे विपक्ष की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष देशभर में हरियाणा सरकार को एक आदर्श के रूप में पेश करता आ रहा है।

इधर चौधरी देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला मोरनी में डेरा जमाये थे, उधर चंडीगढ़ के राजनीतिक हलकों में चर्चा गरम थी कि चौधरी देवीलाल ने आगा-पीछा सोचे बिना चौटाला के कहने में आकर यह सख्त कदम उठा लिया। रणजीत सिंह के घर में जमा हो रहे उनके समर्थक विधायक और चेयरमैन इस मूड में नजर आते थे कि अगर चौधरी देवीलाल ने छह में से एक भी इस्तीफा मंजूर कर लिया, तो सभी सामूहिक रूप से इस्तीफे दे देंगे।

ऐसी बातों की चर्चा चौधरी देवीलाल तक भी गयी। अगर ऐसी अप्रिय बात हो जाती, तो निश्चय ही हरियाणा सरकार का संकट गहरा जाता और इसका लाभ सीधे कांग्रेस को पहुंचता, क्योंकि कांग्रेसी पहले ही प्रचार कर रहे हैं कि सरकार चलाना इनके वश का नहीं है।

सामूहिक इस्तीफों की धमकी तथा राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी की छवि की चिंता ने चौधरी देवीलाल को सोचने को मजबूर कर दिया कि जल्दबाजी में उनके द्वारा उठाया गया यह कदम उनके लिए ही नहीं, पूरे विपक्ष के लिए घातक सिद्ध हो सकता है तथा अबतक की उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। शनिवार की रात को समस्या की पूरी गंभीरता समझकर रविवार को प्रात: ११.३० बजे वे मोरनी से चंडीगढ़ रवाना हुए, ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके।

इधर बिजली एवं सिंचाईमंत्री वीरेंद्र सिंह के आवास पर रणजीत-समर्थकों की बैठक में यह आम राय बनती जा रही थी कि इस विवाद को समाप्त कराया जाये। रविवार को इस गुट को यह काम बहुत आसान नजर आ रहा था, क्योंकि उसी दिन सवेरे चौटाला एक जनसभा को संबोधित करने जलालाबाद (पंजाब में अबोहर के पास) रवाना हो चुके थे। बैठक में राय बनी कि मोरनी चला जाये। वायरलैस पर संपर्क किया गया, तो पता चला कि मुख्यसंत्री खुद चंडीगढ़ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे अपने कार्यालय गये, वहां वीरेंद्र सिंह और डाक्टर पूनिया बुलाये गये, बाद में रणजीत सिंह भी बातचीत में शामिल हो गये तथा दोपहर एक बजे से शुरू हुई बातचीत अपराह्न ढाई बजे इस्तीफे रद्द किये जाने के निर्णय के साथ समाप्त हो गयी। इस्तीफेवाले मंत्रियों ने उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि समारोह के बहिष्कार की कोई मंशा नहीं थी। वास्तव में उन्हें समारोह के समय की पूर्व जानकारी नहीं थी। ऐसा किसी गुटबाजी के आधार पर नहीं किया गया। सभी चौधरी देवीलाल को अपना एकछत्र नेता मानते हैं और उनमें अपनी आस्था व्यक्त करते हैं।

मुख्यमंत्री सीधे अपने कार्यालय गये, वहां वीरेंद्र सिंह और डाक्टर पूनिया बुलाये गये, बाद में रणजीत सिंह भी बातचीत में शामिल हो गये तथा दोपहर एक बजे से शुरू हुई बातचीत अपराह्न ढाई बजे इस्तीफे रद्द किये जाने के निर्णय के साथ समाप्त हो गयी। इस्तीफेवाले मंत्रियों ने उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि समारोह के बहिष्कार की कोई मंशा नहीं थी। वास्तव में उन्हें समारोह के समय की पूर्व जानकारी नहीं थी। ऐसा किसी गुटबाजी के आधार पर नहीं किया गया। सभी, चौधरी देवीलाल को अपना एकछत्र नेता मानते हैं और उनमें अपनी आस्था व्यक्त करते हैं।

ऐसा लिखवाकर चौधरी देवीलाल ने पत्रकारों से तो कह दिया कि बताओ गुटबाजी कहां है? एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं जो चाहता हूं कर लेता हूं, फिर गुटबाजी का क्या मतलब रह जाता है? दूसरी ओर वे अपने विशेष कार्याधिकारी डाक्टर कमलवीर सिंह से कह रहे थे कि तुम चौटाला समर्थक विधायकों की उपेक्षा करते हो, उनके काम नहीं करते, अत: तुम्हें हटाकर रोहतक के एसडीएम आरएस चौधरी को तुम्हारी जगह लगाया जा रहा है।

इस्तीफा-संकट हल हुआ, तो कमलवीर सिंह संकट शुरू हो गया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रणधीर सिंह मलिक के प्रयासों से यह बदलाव भी रुक गया और डाक्टर सिंह अपनी जगह सुरक्षित बने रहे।

—विशेष संवाददाता

कैंसर का इलाज आयुर्वेद के जरिए

मैं ३९ वर्षीय व्यक्ति श्री लक्कप्पा हनुमंयप्पा पुजारी हूं। अपने बाएं पैर के कैंसर के फोड़ों और घावों से पीड़ित था। दोनों तरह की शल्य क्रियाएं-केमोथेरेपी और रेडिएशन (रासायनिक और बिजली द्वारा इलाज) भी मैंने करायी। मगर मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ।

मैं नाउम्मीद हो चुका था। तभी चिक्कडपल्ली, हैदराबाद के आयुर्वेद डाक्टर एम० बाबूराव के कैंसर के इलाज के बारे में एक विज्ञापन कन्नड पत्रिका में देखा। पिछले नौ माह मैंने उनकी दवाएं ग्रहण कीं। अब चिकित्सकीय जांच के जरिए कैंसर विशेषज्ञों ने मुझे पूर्ण निरोग घोषित कर दिया है।

इस बीमारी से पीड़ित अन्य मरीजों के कल्याण के लिए मैं यह विज्ञापन प्रकाशित करवा रहा हूं। वे लोग भी उपचार के लिए इन डाक्टर महोदय से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रस्तुति—
श्री लक्कप्पा हनुमंयप्पा पुजारी
वस्त्र विक्रेता,
पोस्ट-मुदलगी तालुक, गोकाक,
जिला—बेलगाम (कर्नाटक)

सम्पर्क करें

पता	फोन नं०	परामर्श के दिन
आवास		
डा० एम बाबूराव		
कैंसर इन्फर्मरी २-१६१०		
सेडम रोड, मोमुला कोटम		
गुलबर्गा (कर्नाटक राज्य)	२१४५२	प्रत्येक सोमवार, मंगलवार
कैंसर इन्फर्मरी		
१-१-२७१/ चिक्कडपल्ली		
बस स्टाप के नज़दीक		
हैदराबाद-२०	६४७३५	प्रत्येक शुक्रवार
द्वारा होटल राम इंटरनेशनल		
११४, कोडम्पक्कम हाई रोड,	४७३३५०	
मद्रास-६०००३४	४७३४२२	प्रत्येक शनिवार
द्वारा होटल वृन्दावन		
एम०जी० रोड		
बंगलोर	५७३२७१	प्रत्येक रविवार
होटल मिड टाउन	६२८६६३५	
बम्बई	६२०३४७६	
अंधेरी रेलवे स्टेशन (पश्चिम) के सामने	६२८८८८२	प्रत्येक बुधवार

राजभवन में आतंक

आखिर बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में राजभवन के निरीह कर्मचारियों पर ऐसा कहर क्यों बरपा किया कि बेचारे कर्मचारी दर-दर भटकने पर मजबूर हैं? क्या नये राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया राजभवन कर्मचारी यूनियन बन जाने के बाद भी बर्खास्त कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति नहीं बरतेंगे?

अपने लोगों की भरती : राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया अपनी पत्नी के साथ

राजेंद्र प्रसाद आज से लगभग साल भर पहले तक पटना के राजभवन में प्रमुख बावर्ची हुआ करता था। १९६९ से ही राजभवन की नौकरी में लगे राजेंद्र ने बिहार के राज्यपालों और राजभवन में आकर ठहरनेवाले न जाने कितने ही शाही मेहमानों की खातिरी की है। श्रीमती गांधी से लेकर राजीव गांधी तक को राजभवन में भोजन परोसने की कितनी ही यादें उसकी स्मृतियों के खाते में दर्ज है, लेकिन राजेंद्र इन दिनों दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब इस उम्र में भला वह नयी नौकरी कहां तलाशने जाये? पटना राजभवन मे बावर्ची रह चुका ३० वर्षीय युवक जलवा राम भी दुर्गति के दिन भुगत रहा है। नौकरी से निकाले जाने के बाद से जलवा राम राजभवन से कुछ फर्लांग दूर बेली रोड पर एक ठेला लगाकर खाने-पीने की चीजें बेचता है और किसी तरह अपने परिवार का पेट-पाल रहा है। बेंडिक्ट एंथोनी भी पटना राजभवन की रसोई में ही नौकरी पर लगा हुआ था। नौकरी जाने के बाद से उसने बेली रोड पर साइकिल बनाने का काम शुरू कर दिया और इसी काम से कमाये चार पैसों से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। मोहम्मद बशीर भी राजभवन में खानसामा था। नौकरी छूटने के बाद से बशीर का कुनबा फाकाकशी के कड़े दौर से गुजर रहा है। पर बदहाली के ये दिन सिर्फ इन्हीं लोगों के भाग्य में नहीं हैं, बल्कि राजभवन में धोबी की नौकरी में रह चुका मोहम्मद नसीम, चपरासी दीनानाथ और तेजू शाह की भी वही दुर्गति है। इनके अतिरिक्त राजभवन में उपसचिव पद पर रह चुके पंचानन झा तथा उपसचिव स्तर के ही पद पर रहे ज्ञानरंजन बसाक भी गर्दिश के दिन व्यतीत कर रहे हैं। बिहार के राज्यपाल पद पर अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान गोविंद नारायण सिंह ने राजभवन के इन निरीह कर्मचारियों पर जो कहर बरपाया था, उससे आज तक ये बर्खास्त कर्मचारी उबर नहीं सके हैं।

वर्तमान राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के पास अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए राजभवन के इन बर्खास्त कर्मचारियों ने कम कोशिश नहीं की, पर पहाड़िया के दर्शन का सुयोग इन कर्मचारियों को नहीं मिल सका। गोविंद नारायण सिंह ने पटना राजभवन के दस तथा रांची राजभवन के एक कर्मचारी को जिन कारणों से नौकरी से निकाला था, वे अद्भुत थे। प्रमुख बावर्ची राजेंद्र प्रसाद को इसलिए नौकरी से निकाला गया, क्योंकि उसने एक दिन राज्यपाल महोदय के लिए खाने में पालक का साग नहीं तैयार किया था। मोहम्मद बशीर का कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक दिन कलफदार वर्दी में नहीं आया था। धोबी मोहम्मद नसीम को इसलिए बर्खास्त किया गया, क्योंकि उसने चौबीस घंटे में राज्यपाल महोदय के डेढ़ सौ धोती-कुर्ते धोकर नहीं दिये थे। २३ मार्च, १९८८ को उपसचिव पंचानन झा तथा ज्ञानरंजन बसाक को कंपलसरी रिटायरमेंट कराये जाने का फरमान भी राज्यपाल महोदय ने ही दिया था।

भेदभाव: बिहार के राज्यपाल पद से जब गोविंद नारायण सिंह की छुट्टी हो गयी, तो राजभवन के सभी बर्खास्त कर्मचारियों को यह आशा बंधी कि नये राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिया उन लोगों की खोयी हुई आजीविका वापस कर देंगे। पर इन कर्मचारियों का दुख तब और दूना हो गया, जब पहाड़िया ने उन रिक्त स्थानों पर बजाय फिर उनको वापस लाने के अपने लोगों की भरती शुरू कर दी। जून माह में राजस्थान के अपने चार लोगों को बुलाकर पहाड़िया ने नियुक्त कर लिया। ये नियुक्तियां भी अद्भुत ढंग से की गयीं। चतुर्थ श्रेणी में प्रभुदयाल तथा सुआलाल की नियुक्ति राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों कीं। इन दोनों कर्मचारियों ने अपने आवेदन पत्र में उन्हीं का पता भी दिया था— मार्फत, श्रीमती शांति पहाड़िया, बीकानेर हाउस एनेक्सी, पंडारा रोड, नयी दिल्ली। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इंका सांसद शांति पहाड़िया जगन्नाथ पहाडिया की पत्नी हैं। मजेदार बात तो यह है कि प्रभुदयाल व सुआलाल ने जिस पते से अपने आवेदन पत्र दिये थे, ठीक उसी पते पर उनकी ड्यूटी भी लगा दी गयी। वे दोनों शांति पहाड़िया की तीमारदारी में लगे रहते हैं। राज्यपाल के आप्त सचिव ने बाकायदा निर्देश जारी किया था कि राज्यपाल महोदय के दिल्ली स्थित कैंप आफिस हेतु कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता है और उसी के तहत ये कर्मचारी नियुक्त किये गये। वैसे आज तक कभी बिहार के किसी राज्यपाल ने दिल्ली में अलग से अपना कैंप आफिस नहीं बनाया था, क्योंकि दिल्ली स्थित बिहार भवन में ही राज्यपाल के दिल्ली प्रवासकाल के लिए सारा इंतजाम है।

फाकाकशी : बर्खास्त मोहम्मद बशीर

पहाडिया द्वारा निजी सहायक पद पर दो नियुक्तियों ने भी राजभवन के टूटे-हारे बर्खास्त कर्मचारियों को उत्तेजित कर दिया। इन दो निजी सहायकों में एक धरम सिंह पहाड़िया रिश्ते में राज्यपाल महोदय के भतीजे हैं और दूसरे हैं, प्रकाश परेवा। इन दोनों को भी ज्यादातर दिल्ली में ही शांति पहाड़िया के पास हाजिरी बजानी पड़ती है। राजभवन के कर्मचारी सूत्रों का कहना है कि धरम सिंह पहाड़िया बीए भी पास नहीं हैं, जबकि निजी सहायक पद के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। जगन्नाथ पहाडिया और भी नियुक्ति करने जा ही रहे थे कि पटना राजभवन के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी का इजहार 'राजभवन कर्मचारी संघ' का गठन करके कर दिया। राजभवन के कर्मचारियों की यूनियन पहले कभी नहीं बनी थी। दरअसल, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आयी थी कि कर्मचारियों को यूनियन बनाने की आवश्यकता महसूस होती। पर गोविंद नारायण सिंह के समय बुरी तरह प्रताड़ित होने और उसके बाद प्रताड़ना से उबारने की बर्खास्त कर्मचारियों की फरियाद के प्रति जगन्नाथ पहाडिया की उदासीनता ने आखिरकार राजभवन के कर्मचारियों को यूनियन गठित करने पर विवश कर दिया। इस यूनियन में चतुर्थ श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी के भी कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन के एक प्रवक्ता के मुताबिक, "जब हमें यह लगा कि गोविंद नारायण सिंह के कड़वे अनुभव के बाद अब जगन्नाथ पहाड़िया से भी उसी किस्म का बरताव मिलने की संभावना है, तो तत्काल एक मत से यूनियन का गठन किया गया।" राज्यपाल पहाड़िया को जब राजभवन कर्मचारी यूनियन के गठन की सूचना मिली, तो वे सख्त नाराज हुए। दरअसल, कर्मचारियों ने राज्यपाल को बाकायदे लिखित सूचना दी थी कि उन लोगों ने यूनियन बनाया है और राज्यपाल उसे मान्यता दें। कर्मचारियों को मनाने के लिए राज्यपाल की सांसद पत्नी शांति पहाड़िया ने मोर्चा संभाला। ६ जुलाई को शांति पहाडिया ने सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को चाय पर आमंत्रित किया। शांति पहाड़िया की इस सदाशयता से राजभवन के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी चकित हो उठे। शांति पहाड़िया ने चाय पर जुटे कर्मचारियों को समझाने की भरसक कोशिश की कि वे लोग यूनियन की बात दिमाग से निकाल दें। पर कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कर्मचारियों ने यूनियन की बैठक में तय किया कि राजभवन से बर्खास्त कर्मचारियों की वापसी के लिए वे लोग संघर्ष करेंगे तथा राजभवन में अनाप-शनाप नियुक्तियों पर भी कड़ी नजर रखेंगे।

अब साइकिल मिली: बेंडिक्ट एंथोनी

राजभवन से सड़क पर: खाने का सामान बेचते हुए बर्खास्त बावर्ची जलवा राम

क्षुब्ध कर्मचारी : उपसचिव रह चुके पंचानन झा के मामले में भी जगन्नाथ पहाड़िया के रवैये ने राजभवन कर्मचारियों को क्षुब्ध कर दिया। दरअसल, पंचानन झा और ज्ञानरंजन बसाक को जब गोविंद नारायण सिंह ने कंपलसरी रिटायरमेंट की चिट्ठी थमवा दी थी, तो न्याय के लिए पंचानन झा अदालत की शरण में चले गये थे। ज्ञानरंजन बसाक अदालत मे इसलिए नहीं गये, क्योंकि वे इस बात की प्रतीक्षा में थे कि पंचानन झा के मामले मे अदालत का जो फैसला होगा, उसी के अनुरूप उनका मामला भी तय होगा। २५ मई, १९८९ को पटना उच्च न्यायालय ने पंचानन झा के मामले में फैसला देते हुए टिप्पणी की कि राज्यपाल को यंह अधिकार है ही नहीं कि वे अपने सचिवालय के कर्मचारी को बर्खास्तगी या कंपलसरी रिटायरमेंट का आदेश दे सकें। इसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। बहरहाल, पंचानन झा के पक्ष में जब पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ गया, तो फैसले की प्रति राज्यपाल पहाड़िया के पास पेश हुई। राज्यपाल ने महाधिवक्ता रामबालक महतो की राय इस संबंध में लेकर अदालत के फैसले के साथ उसे नत्थी करते हुए मंत्रिपरिषद को विचारार्थ भिजवा दिया। २६ मई '८९ को महाधिवक्ता महतो ने पंचानन झा के मसले पर राज्यपाल को प्रेषित टिप्पणी में कोई प्रतिकूल राय नहीं दी थी। पर राजभवन के सूत्रों के मुताबिक पंचानन झा वाले मामले को मंत्रिपरिषद में भिजवाने के पश्चात पहाड़िया किसी कार्यवश दिल्ली चले गये थे और जब वे दिल्ली से लौटे, तो अचानक उन्होंने महाधिवक्ता को पंचानन झा के प्रसंग में फिर से कानूनी राय देने को कहा। लिहाजा, १८ जून '८९ को महाधिवक्ता ने विधि विभाग के सचिव को प्रेषित टिप्पणी में लिखा कि यह मामला क्योंकि राजभवन के कर्मचारियों के संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है और कई गंभीर संवैधानिक प्रश्न इसमें उलझे हैं, इसलिए यह एक ऐसा केस है जिसको लेकर राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। राजभवन के कर्मचारी राज्यपाल के रुख में अचानक इस परिवर्तन से बेहद परेशान हुए। सबको आश्चर्य हुआ कि बिना किसी हील-हुज्जत के पंचानन झा के मामले को मंत्रिपरिषद में भेजने के बाद अचानक राज्यपाल को फिर क्या हो गया? राजभवन के एक कर्मचारी का कहना है कि इस घटना से यह साबित हो गया कि गोविंद नारायण सिंह तथा जगन्नाथ पहाड़िया में कोई अंतर नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि गोविंद नारायण सिंह बहुत बोलते थे और पहाड़िया बोलते ही नहीं। पहाड़िया के स्थितप्रज्ञ भाव का अनुभव ज्ञानरंजन बसाक को बड़े विचित्र ढंग से हुआ। बेचारे बसाक बहुत मुश्किल से राज्यपाल के पास अपनी बात कहने के लिए समय पा सके। बसाक ने नौकरी से कंपलसरी रिटायरमेंट वाली अपनी कहानी जब राज्यपाल को सुनायी तो पहाड़िया खामोश शून्य में देखते रहे। बसाक चार-पांच मिनट तक इस प्रतीक्षा में खड़े रहे कि अब शायद राज्यपाल का मौन टूटे और वे कुछ कहें। पर पहाड़िया का मौन जब उन्हें टूटता नजर नहीं आया, तो परेशान हाल बसाक भारी मन से उनके चैंबर से बाहर आ गये।

—विकास कुमार झा

छाया: भास्कर मुखर्जी, दीपक कुमार

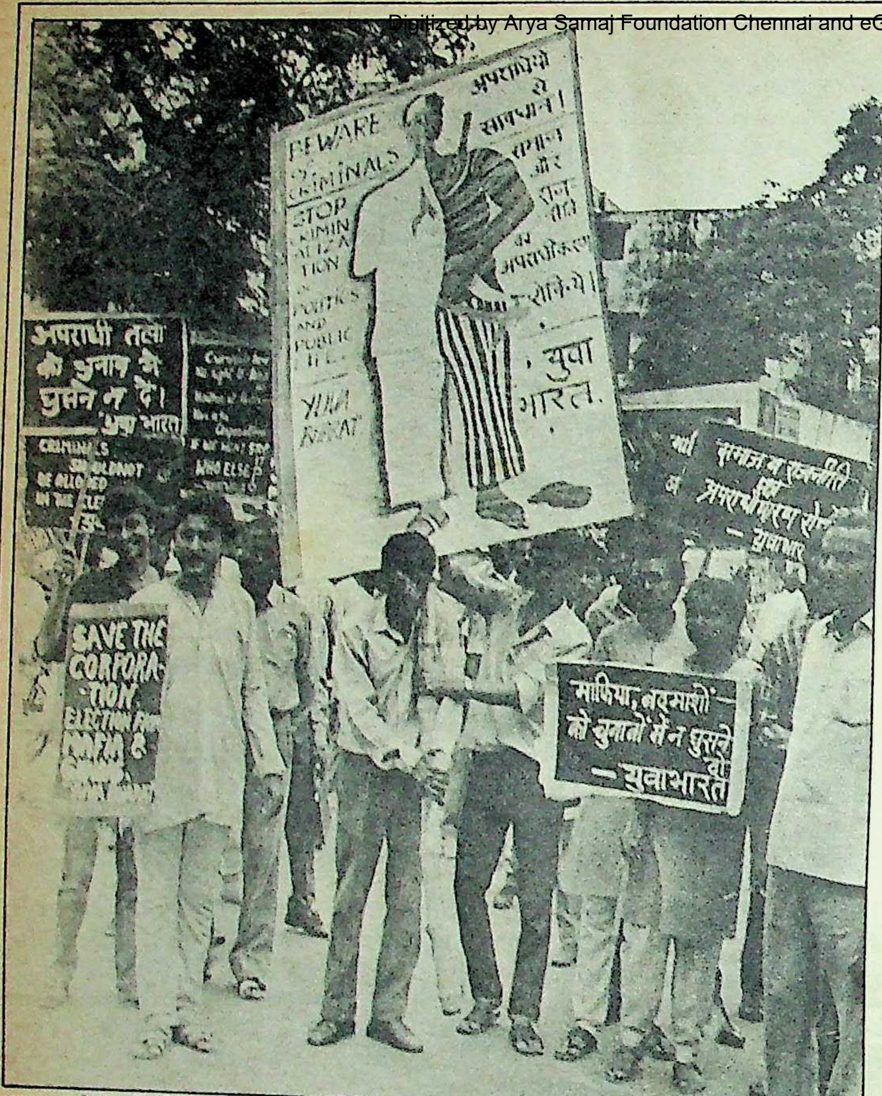
BEWARE OF CRIMINALS
STOP CRIMINALIZATION IN POLITICS AND PUBLIC LIFE
YUVA BHARAT
अपराधियों से सावधान!
युवा भारत
अपराधी तत्वों को चुनाव में घुसने न दें। युवा भारत
SAVE THE CORPORATION ELECTION
माफिया, बदमाशों को चुनावों में न घुसने दो — युवाभारत

नक्कारखाने में तूती की आवाज: आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार

छाया : मनमोहन शर्मा

इलाहाबाद और लखनऊ महापालिका चुनाव

दलों के बजाय दादाओं का वर्चस्व

गत ३० जुलाई को एक लंबे अरसे के बाद संपन्न हुए इलाहाबाद और लखनऊ नगर महापालिकाओं के चुनाव में गैरराजनीतिक प्रत्याशियों को इतनी भारी संख्या में सफलता कैसे मिली?

इलाहाबाद में १९ वर्षों बाद गत ३० जुलाई को संपन्न हुए नगर महापालिका के चुनाव ने इलाहाबाद के उन बुजुर्ग लोगों को चौंका कर रख दिया है, जिन्होंने इस शहर का पुराना जमाना देखा है। इस शहर ने जिन लोगों को यहां सभासद व मेयर बनाया था, उनमें पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, कैलास नाथ काटजू प्रभृति ऐसे मनीषियों के नाम शामिल हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में पूरे देश के मार्गदर्शक बने, विश्वविख्यात हस्तियों के रूप में शुमार किये गये और जिनकी वजह से इलाहाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ, लेकिन नगर महापालिका के इस चुनाव में ८० सीटों के लिए ९०७ प्रत्याशियों के मैदान में होने के बावजूद जिन लोगों के नाम रोशन हुए और मतदाताओं ने जिन्हें रिकार्ड तोड़ मतों से विजयी बनाया, उनमें कुछ ऐसी हस्तियां हैं, जिनका जिक्र राजनीति की किसी किताब में तो नहीं, लेकिन पुलिस की किताब में उनकी ख्याति काफी विस्तार से दर्ज हैं। कहा जाता है कि इस चुनाव में विजयी ८० में से ऐसे सभासदों की संख्या २६ है, जिनकी खुफिया जांच यह पता करने के लिए हो रही है कि क्या इन्हें न्यायालय ने कभी दंडित किया था या सजा भुगतने के बाद पांच वर्षों के दौरान क्या उन्होंने फिर कोई अपराध किया? क्योंकि इन दोनों ही सूरतों में इनके चुनाव रद्द हो सकते हैं।

३० जुलाई को मतदान के दिन इलाहाबाद के आठ वार्डों की १६ सीटों के मतदान केंद्रों में फर्जी वोट डलवाने के सारे सभव साधनों का इस कदर इस्तेमाल हुआ कि प्रशासन को उन स्थानों पर फिर से मतदान कराना पडा। पुलिस सूत्रों ने स्वीकार किया कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि मतदान के दिन इतनी भारी मात्रा में गड़बड़ी होगी। उसे यह भी अंदेशा नहीं था कि चुनाव परिणाम निकलने के बाद शुरू हुए विजय जुलूसों में इतने बम-पत्थर और गोलियां चलेंगी कि इलाहाबाद में दंगा होने की नौबत आ जायेगी। पुलिस और प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी और सूझबूझ से दंगा नहीं होने दिया, जबकि इन चुनावों के दौरान हुई हिंसा में तीन लोगों के मारे जाने और उन दिनों इलाहाबाद में शहर और शहर के बाहर के आपराधिक तत्वों की भारी संख्या में मौजूदगी के कारण दंगा होने के सारे आसार व साज-सामान मौजूद थे। अपर जिलाधिकारी (शहर) मोहन स्वरूप और पुलिस अधीक्षक ओपी सिह की जोड़ी ने उत्तेजना के तीन दिन और तीन रातों में जिस चुस्ती और चौकसी से काम लिया, उसी का नतीजा था कि शहर आशंकित भीषण हादसे से बच गया। दोनों ही इलाहाबाद के भूगोल और इतिहास से वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने उन स्थानों की ऐसी अघोषित नाकेबंदी की कि असामाजिक तत्वों के इरादे धरे-के-धरे रह गये। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इलाहाबादवासियों के लिए १९ वर्ष बाद आया यह खुशी का मौका आतंक और भय के साये में गुजरा। प्रशासन ने दंगे की आशंका के कारण विजय उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

लखनऊ में भी वही हाल : तीस जुलाई को लखनऊ नगर महापालिका के लिए हुए चुनाव में भी किसी राजनीतिक दल या राजनेता की नहीं, बल्कि बाहुबलियों की ही तूती बोलती रही। वैसे यहां भी ८० सीटों पर १०५। प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सर्वाधिक नाम रोशन हो रहा था माफिया सरगना के रूप में चर्चित अरुण शंकर शुक्ला उर्फ 'अन्ना' का। एक लखनऊवासी के अनुसार, "सत्तारूढ कांग्रेस और जनता दल, पार्टी के सारे साधनों को झोंक देने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मसलों पर धुआंधार सैद्धांतिक भाषण झाड़ने के बावजूद बमुश्किल क्रमश: ८ और १२ से

अधिक सीटें नहीं जीत सके, जबकि अरुण शंकर शुक्ला और उनके आदमियों ने इतनी सीटें बड़ी आसानी से जीत लीं। अन्ना के भाई कैलाश शंकर शुक्ला का नाम भी सभासदों की सूची में दर्ज हो गया है।" लखनऊ में पुलिस और प्रशासन इलाहाबाद की अपेक्षा कहीं अधिक चौकन्ना था। अनेक मतदान केंद्रों पर घपलेबाजी की छिटपुट घटनाएं तो हुईं, लेकिन वजीरगंज वार्ड के ४ मतदान केंद्रों को छोड़कर अन्यत्र कहीं पुन: मतदान की नौबत नहीं आयी।

लखनऊ और इलाहाबाद के इन चुनावों की एक उल्लेखनीय बात यह भी थी कि दोनों महानगरों में एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकी, जबकि लखनऊ में ४२ और इलाहाबाद में १३ महिलाए चुनाव मैदान में उतरी थीं। इलाहाबाद की एक महिला प्रत्याशी ने अपना नाम न छापने का अनुरोध करते हुए 'माया' को बताया, "दादाओं के आतक के कारण उस दिन सभी महिलाएं मतदान तक नहीं कर सकीं। राजनीति का यदि इसी तरह अपराधीकरण होता रहा, तो चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, कोई महिला चुनाव लड़ने का सपना तक नहीं देख सकेगी।"

संतुष्ट भाजपा: उत्तर प्रदेश के कुल आठ महानगरों में से इलाहाबाद और लखनऊ को छोड़कर शेष छह महानगरों (आगरा, बरेली, मेरठ, बनारस, गोरखपुर और कानपुर) की नगरपालिकाओं के चुनाव पहले ही (नवंबर, १९८८) हो चुके थे। भाजपा ने इन सभी स्थानों पर अपने नाम, चुनाव चिह्न और झंडे तले अपने प्रत्याशियों को लड़ाया था और परिणाम भीं उसके पक्ष में रहे। जहां उत्तर प्रदेश से भाजपा का एक भी सांसद नहीं है, प्रदेश विधान सभा में भी उसकी स्थिति नगण्य है और पंचायत चुनावों में भी उसे उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले, वहीं पूर्व में हुए छह महानगरों की नगर महापालिकाओं के चुनावों में उसने ऐसी बाजी मारी कि तीन महानगरों (आगरा, बरेली, मेरठ) में उसके मेयर हैं, बनारस में उसके ३४, गोरखपुर में १४ और कानपुर में उसके १६ सभासद हैं।

इलाहाबाद और लखनऊ नगर महापालिकाओं के चुनाव में भी केवल भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसने अपने चुनाव चिह्न 'कमल' पर अपने क्रमश: ६७ और ७७ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान मे उतारा था। अन्य कांग्रेस-इ, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मुस्लिम मजलिस आदि दलों ने परोक्ष रूप से चुनाव लड़ा था। इसका कारण यही था कि भाजपा को छोडकर कोई अन्य राजनीतिक दल यह नहीं चाहता था कि सिर पर खड़े आमचुनाव के माहौल में उनके दल का शक्ति परीक्षण महानगरपालिका के चुनाव में ही हो जाये। भाजपा को पूरी आशा थी कि रामजन्म भूमि आंदोलन का उत्प्रेरक गढ़ होने के कारण इलाहाबाद और लखनऊ की हिंदू आबादी भाजपा के सिर पर ही सेहरा बांधेगी और इस विजय से पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा जो आसन्न आमचुनाव में अधिकतम सीटें जीतने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद में भाजपा को एक समान मत नहीं मिले। लखनऊ में जहां भाजपा ने ८० स्थानों में से ३२ सीटों पर विजय पायी, वहीं इलाहाबाद में उसे बमुश्किल दस सीटों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा के एक पराजित प्रत्याशी का कहना था, "इलाहाबाद में भाजपा की लोकप्रियता लखनऊ से कम नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में जहां भाजपा के विद्रोही प्रत्याशियों के कारण भाजपा के वोट कटे, वहीं इलाहाबाद में भाजपा का चुनाव अभियान वैसा व्यवस्थित नहीं था, जैसा कि लखनऊ में था, अन्यथा इलाहाबाद में भी भाजपा २५ से ३० स्थानों पर विजय प्राप्त करती।" लेकिन, नगर भाजपा के अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना था, "हमें आशा के अनुकूल ही परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमने १५ सीटों की उम्मीद लगायी थी, जिनमें से दस हमें मिलीं और पांच सीटें हम ५ से १०० मतों से ही हारे। यदि लखनऊ के समान यहां भीं पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता और फर्जी वोट न पड़ते, तो हम बड़ी आसानी से ये पांच सीटें भी निकाल लेते।"

कांग्रेस को झटका: भाजपा चुनाव परिणामों से संतुष्ट है और आपराधिक छवि के लोगों के नाम इन चुनावों में रोशन हुए, तो बकौल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के सबसे ज्यादा नाम कांग्रेस का डूबा। इलाहाबाद और लखनऊ महापालिका चुनावों में वह खुले शक्ति परीक्षण से तो बच गयी, लेकिन अपयश से नहीं बच सकी। अपने नाम व निशान पर उसके प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मतदाता जानते ही न हों कि कांग्रेस के कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल के एक नेता का कहना है, "इलाहाबाद में कांग्रेस समर्थित विजयी प्रत्याशियों की संख्या जहां सिर्फ १२ रही, वहीं लखनऊ में वह केवल आठ स्थान ही जीत सकी। लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद में कांग्रेस के कर्णधार इस कोशिश में हैं कि मेयर के चुनाव में अपने प्रत्याशी को वे येन केन प्रकारेण अधिकतम मत दिलवाएं जिससे बाद में यह साबित हो कि कांग्रेस के अधिक प्रत्याशी चुनाव जीते थे।" प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष मुलायम सिंह का कहना है, लखनऊ में तो कांग्रेस की हार स्पष्ट है। भाजपा के ३२ और जनता दल के अरुण शंकर अन्ना के साथियों सहित २२ सभासदों के कारण स्पष्ट है कि लखनऊ में कांग्रेसी मेयर का कांग्रेसी सपना पूरा नहीं होगा।" लेकिन इलाहाबाद में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक वाजपेयी का दावा है कि उन्हें ३६ सभासदों का समर्थन हासिल है, लेकिन असलियत तो २३ अगस्त को मेयर के चुनाव के बाद ही उजागर हो सकेगी। तथापि राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि लखनऊ और इलाहाबाद में कांग्रेस के हौसले पस्त हैं।

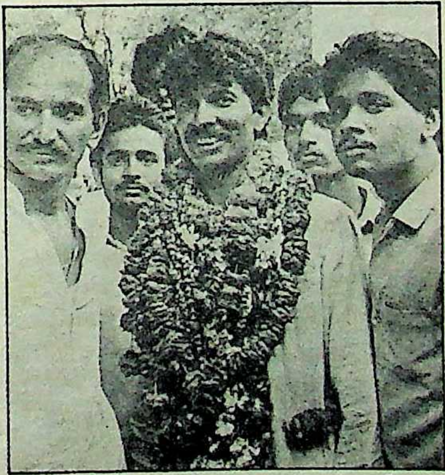

बुलंद हौसले: अरुण शंकर अन्ना (बाएं) अपने समर्थक प्रत्याशी के साथ

बहरहाल, नगर महापालिकाओं के अधिकार काफी सीमित हैं। एक जमाना था जब मेयर ही उपनगर अधिकारी, सहायक नगर अधिकारी, नगर अभियंता आदि की नियुक्ति करता था लेकिन १९७३ के बाद से नगर महापालिकाओं पर आईए एस अफसर हावी हैं। जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण को महापालिका से अलग कर दिया गया है। एक नवनिर्वाचित सभासद के अनुसार, "अब नगर महापालिका का प्रमुख काम नगर की सफाई कराना भर रह गया है।" लेकिन इलाहाबाद के एक बुजुर्ग नेता का कहना था कि महत्व इस बात का नहीं है कि नगर महापालिकाओं में सभासद और मेयर कितने अधिकार संपन्न हैं, महत्व इस बात का है कि एक लंबे अर्से बाद इन महापालिकाओं का संचालन जनता द्वारा चुने हुए लोगों के हाथों में आया है, तो कुछ-न-कुछ काम तो जरूर होगा।" लेकिन एक इलाहाबादी ने आशंका भी व्यक्त की कि जिस तरह के अपराधी लोग इस चुनाव में विजयी हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि आम जनता का शोषण करने के लिए सरकारी अफसर तो पहले से ही मौजूद थे, अब नगरवासियों का शोषण करने के लिए एक नयी जमात पैदा हो जायेगी।" इन चुनावों में असामाजिक तत्वों की शिरकत को देखते हुए एक व्यक्ति ने तो यहां तक कहा, "एक बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि आनेवाले चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए अब अच्छे सिद्धांत और अच्छे व्यक्ति उतने कारगर नहीं होंगे, जितने कि वे जिनके बाजुओं में ताकत और गांठ में रुपयों की थैली होगी।" तथापि उम्मीद रखनी चाहिए कि इलाहाबाद महानगरपालिका के निर्वाचित सदस्य यहां की गौरवमयी परंपरा का प्राणपण से पालन करेंगे। उनका कार्य-उत्तरदायित्व केवल नगरवासियों का हित चिंतन करने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद एक शहर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है और तीर्थराज प्रयाग के कारण यह नगर देशभर से प्रतिवर्ष यहां आनेवाले लाखों लोगों का मेजबान भी।

—विनोद मिश्र

नस्ली वाडिया की हत्या की साजिश

जानलेवा प्रतियोगिता : नस्ली वाडिया

१ अगस्त, १९८९। रात नौ बजे प्रसारित होनेवाले टीवी सीरियल 'महानगर' का एक एपीसोड दिखलाया जा रहा था—भारत से कुछ वर्ष पहले नौकरी की तलाश में विदेश गया श्याम आहूजा (शेखर कपूर) अरबपति बन कर लौटता है और जमी-जमायी कंपनियों को खरीदने की योजना बनाते-बनाते एक उद्योगपति (मोहन अगाशे) की कंपनी एसके इंटरनेशनल के शेयर खरीदने शुरू कर देता है। शेयर खरीदने के मार्ग में प्रमुख बाधक शेयरधारक श्री जौहरी को उनकी जवानी की भूलों के चित्र दिखलाकर उन्हें अपने मकान में लाकर तब तक के लिए बंद कर देता है, जब तक पब्लिक इशू के शेयर बाजार में नहीं आ जाते और उन्हें श्याम आहूजा खरीद नहीं लेता।

इस सीरियल को देखते-देखते दर्शकों को अचानक स्वराज पाल बनाम दिल्ली क्लाथ मिल्स का कुछ इसी तरह का हुआ विवाद याद आ जाता है, लेकिन इस एपीसोड के तुरंत बाद दूरदर्शन के अंग्रेजी समाचार की, सुनने में मामूली-सी लगने वाली, एक खबर लोगों को चौंका देती है और इसके बाद सुर्खियों का बाजार गर्म हो जाता है। खबर थी एक प्रख्यात औद्योगिक प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक की, दूसरे प्रमुख उद्योगपति की हत्या की साजिश में गिरफ्तारी। इत्तिफाक से यहां भी एक पक्ष द्वारा अधिकृत एक बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान के नौ सौ करोड़ रु० के पब्लिक इशू एक पखवारे के भीतर ही बाजार में आने वाले थे।

वाडिया को चुनौती : बांबे डाइंग के मालिक उद्योगपति नस्ली वाडिया को लगता था कि उनके सितारे गर्दिश में हैं। वे विदेश से ११ जुलाई '८९ को ही लौटे थे। आते ही पुलिस ने उन्हें इस आशय का हुक्मनामा थमा दिया था कि वीसा की अवधि खतम होने तक ही, यानी २४ घंटे तक ही वे भारत में रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वाडिया ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं। उनके भारतीय नागरिक होने के दावे को सरकार ने अदालत में चुनौती दे रखी है।

१५ जुलाई को नस्ली वाडिया से पुलिस के कुछ अधिकारी मिले। उन्होंने वाडिया को संरक्षण देने के इरादे से दो हथियारबंद पुलिसकर्मी उनके साथ रखने की उनसे इजाजत मांगी, लेकिन वाडिया इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं हुए। पुलिस की इस सलाह पर वे कुछ चिढ़ भी गये। उन्हें लगा कि उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी तथा कामकाज व गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ही पुलिस कोई बहाना तलाश रही है, लेकिन अंततः उन्हें राजी होना पड़ा।

पंद्रह दिन बाद एक अगस्त '८९ को एस्प्लानेड कोर्ट, बंबई के एक छोटे-से कमरे में २३वीं अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जेडब्ल्यू सिंह के सामने पुलिस ने दो अभियुक्तों को खड़ा किया। इनमें एक रिलायंस उद्योग में जनसपर्क तथा समन्वय विभाग के ४८ वर्षीय महाप्रबंधक कीर्ति ब्रजलाल अंबानी उर्फ शाह थे तथा दूसरा व्यक्ति था, अर्जुन बाघजी बाबरिया उर्फ 'प्रिंस', व्यवसाय-आर्केस्ट्रा, उम्र-२२ वर्ष।

दोनों पर नस्ली वाडिया की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप था। खुफिया पुलिस ने तफ्तीश कर अदालत के सामने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक कीर्ति अंबानी ने नस्ली वाडिया को जान से मारने की योजना बनायी। प्रिंस की मार्फत इस काम की 'सुपारी' (किराये पर हत्या करने की जिम्मेदारी) दी गयी। पुलिस के अनुसार यह साजिश आठ महीने पहले नवंबर, १९८८ में तैयार की गयी थी। वाडिया की गाड़ियों के नंबर, आने-जाने का समय तथा रास्ता षड्यंत्रकारियों की नजर में था।

रहस्योद्घाटन : सूत्रों के अनुसार इस मामले का रहस्योद्घाटन भी बड़े अजीबोगरीब ढंग से हुआ था। अर्जुन बाबरिया किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस-तहकीकात के दौरान उसने 'सुपारी' पर हत्या करने की उस साजिश की जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन कीर्ति अंबानी के वकील कृष्णकांत देसाई ने कीर्ति को हिरासत में लेने का विरोध करते हुए कहा कि 'पुलिस उद्योगपतियों की स्पर्धा को षड्यंत्र का रूप दे रही है।' अर्जुन बाबरिया ने अलग से कोई वकील करने के बजाय अपनी पैरवी खुद की।

बंबई के पुलिस आयुक्त वसंत सराफ के निर्देश पर दोनों अभियुक्तों को खास पुलिस दस्ते के साथ लुंगी से मुह ढक कर अदालत भेजा गया था। वहां सरकारी वकील फीरोज वकील ने अभियुक्तों की ताकत तथा दबाव डालने के खतरे को देखते हुए अदालत से अनुरोध किया कि अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत दी जाये। महानगर दंडाधिकारी सिंह ने अभियुक्तों को ८ अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। मजे की बात यह है कि एक अगस्त को दोनों की गिरफ्तारी की जो प्रेस सूचना जारी की गयी थी, उस पर किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं था। एक सूचना के अनुसार एक सहायक पुलिस आयुक्त को जब तैयार प्रेस रिलीज दिखलायी गयी, तब उसके नाम के ऊपर पुलिस आयुक्त वसंत सराफ तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त अरविंद इनामदार का भी नाम था, लेकिन जब उन दोनों का नाम प्रेस रिलीज से हटा दिया गया, तो उस सहायक आयुक्त ने भी अपना नाम प्रेस रिलीज से हटा दिया। इस बात का पुलिस ने खंडन भी नहीं किया। अजीब बात है, इतने बड़े मामले के 'भंडाफोड' का श्रेय कोई भी पुलिस अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं है!

दिल्ली कनेक्शन : एक तरफ रिलायंस ग्रुप के प्रभावशाली 'दिल्ली कनेक्शन' की चर्चा होती रही, तो दूसरी तरफ नस्ली वाडिया की विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार एवं किसान नेता शरद जोशी के साथ 'घनिष्ठ' संबंधों की चर्चा भी सुर्खियों में रही। रिलायंस ग्रुप के एक विरोधी का कहना था कि 'धीरूभाई' अपने 'दिल्ली कनेक्शन' के बल पर कपडा उद्योग के गॉडफादर बनना चाहते थे, वे काफी हद तक केंद्र की कपड़ा-नीतियों के कर्ता-धर्ता भी थे।' लेकिन इस बात का रिलायंस ग्रुप की तरफ से खंडन किया जाता रहा।

एक सूत्र के अनुसार विश्वनाथ प्रताप सिंह की वाडिया समर्थक नीति के ही कारण प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस द्वारा की गयी मशीनरी की खरीद-फरोख्त, आयकर खाते आदि की जांच-पड़ताल की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहले वित्त मंत्रालय, फिर दल से अलग हटने पर नस्ली वाडिया के विरुद्ध जो मुकदमे शुरू किये गये, उसके पीछे भी इस व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को ही कारण बतलाया गया।

इस बीच एक अफवाह और भी उड़ी। कर्नाटक सरकार का पतन होने के बाद हरियाणा सरकार के पतन की जो योजना बनी, उसके पीछे रिलायस ग्रुप का हाथ माना गया। इसे तब और हवा मिली जब चौधरी देवीलाल के पुत्र तथा हरियाणा के कृषिमंत्री रणजीत सिंह ने अपनी बंबई-यात्रा के दौरान कहा, "ऐसे कई अंबानी थैलियां खोलने के लिए तैयार होंगे, परंतु वे भूल जाते हैं कि दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरी है। हरियाणा सरकार को

हाथ लगाया, तो पल भर में लाखों लोग दिल्ली कूच कर, घेरा डाल देंगे।'' लेकिन हरियाणा की सरकार न तो गिरी और न ही इसकी योजना में अंबानी का हाथ होने की पुष्टि हो सकी।

रिलायंस पर आरोप: रिलायंस ग्रुप पर दो और आरोप लगाये गये थे—(१) उन्होंने उस समय एक टीवी सीरियल 'गोर्बाचिव से राजीव तक' बनाने की योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी थी, जब देश में एक तरफ बोफोर्स तोपों की गड़गड़ाहट थी और दूसरी तरफ 'पेरेस्त्रोइका' की धूम थी। (२) रिलायंस आगामी चुनाव में कांग्रेस के चुनाव-प्रचार की जिम्मेदारी लेना चाहता था।

अब क्योंकि तीनों घटनाएं नहीं घटित हुईं, इसलिए ये अफवाहें सिर्फ अफवाहें बनकर ही रह गयीं और यह मान लिया गया कि रिलायंस विरोधी गुट इस तरह की अफवाहें फैलाकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और धीरूभाई अंबानी के बीच संशय और मतभेद की दीवार कायम करना चाहता है। इसी सिलसिले में दो और बातों की चर्चा हो रही है—नारायण दत्त तिवारी का दिल्ली से हटाया जाना तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक मोहन कात्रे को, जो महाराष्ट्र के पुलिस महानिरीक्षक पद के दावेदार भी थे, ३१ अक्तूबर '८९ तक एक्सटेंशन देना। कहा जा रहा है कि अंबानी की ताकत को संतुलित करने के लिए यह किया गया, क्योंकि इन तीनों को अंबानी के करीब माना जाता है।

इस संदर्भ में इस चर्चा का उल्लेख भी जरूरी है कि अक्तूबर-नवंबर '८८ में, राजीव गांधी और वाडिया के बीच गलतफहमियां दूर करने की कोशिशें हुई थीं। एक सूचना के अनुसार जेआरडी टाटा, रतन टाटा के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने इन 'गलतफहमियों को दूर करने की नये सिरे से कोशिश की।

सूत्रों के अनुसार शरद पवार के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद इन प्रयासो में तेजी आयी। यहां एक दिलचस्प बात का वर्णन करना भी जरूरी है—वाडिया-पवार के बीच दोस्ती को मजबूती का सीमेंट लगाया था, फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान ने। आज से कुछ वर्ष पहले ये तीनों लंदन में एक दूसरे के निकट आये। वाडिया तथा जीनत पुराने दोस्त हैं। राजनीतिक दांवपेंच में माहिर पवार के कहने से वाडिया ने सरकारी योजनाओं में गहरी दिलचस्पी ली। यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता या आगे चलता रहा, तो वे वित्त, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालयों की अनापत्ति के साथ कुछ लाइसेंस झटकने में सफल होंगे। इन उद्योगपतियों के बदलते राजनीतिक रिश्तों के संदर्भ में इस षड्यंत्र को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। (देखिए बाक्स) नवंबर १९८८ में बंबई के अपराध जगत को वाडिया की हत्या करने की सुपारी दी गयी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सही रकम नहीं बतलाते, परंतु एक उच्च स्तरीय सूत्र ने 'माया' को बताया कि प्राप्त दस्तावेजों से लाखों रुपए दिये जाने की पुष्टि होती है। यह बात भूली नहीं जा सकती कि नवंबर १९८८ से मार्च '८९ के बीच बंबई में माफिया गिरोहों के कई बड़े दिग्गजों की लाशें बिछी थीं। उन दिनों हत्याओं का लंबा सिलसिला चला था। पुलिस का कहना है कि भिंडी बाजार की चाल में रहनेवाले बाबरिया उर्फ प्रिंस के माफिया गिरोहों से रिश्ते हैं।

षड्यंत्र: बंबई पुलिस का कहना है कि वाडिया की हत्या की 'सुपारी' नवंबर १९८८ में दी गयी थी। हत्या के लिए कितनी रकम तय हुई और कितना अग्रिम भुगतान हुआ, इसकी सही जानकारी देने के लिए पुलिस अधिकारी तैयार नहीं हैं। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि प्राप्त सबूतों से साबित होता है कि लाखों रुपए तय हुए थे। बहरहाल, इन सबूतों की असलियत तो अदालत में खुलेगी, लेकिन यह बात अजीब लगती है कि कोई बड़ा उद्योगपति अपने प्रतिद्वंद्वी उद्योगपति की हत्या की साजिश करेगा। किसी व्यक्ति विशेष के सफाये से औद्योगिक चुनौती कमजोर नहीं होती। फिर इस तरह की घटनाओं का प्रतिशोधात्मक सिलसिला चलता है, इसलिए कोई उद्योगपति अपनी शक्ति और समय ऐसे घिनौने काम में लगाना नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा नही है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। १९८५ में ओरके मिल्स के कपल मेहरा के बेटे पंकज पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान तो बच गयी थी, पर उनके गंभीर चोटें आयी थीं। ओरके मिल्स के कारखाने भी पाताल गंगा क्षेत्र में हैं और वे भी औद्योगिक टकराव से मुक्त नहीं हैं।

संपर्क सूत्र: जीनत अमान

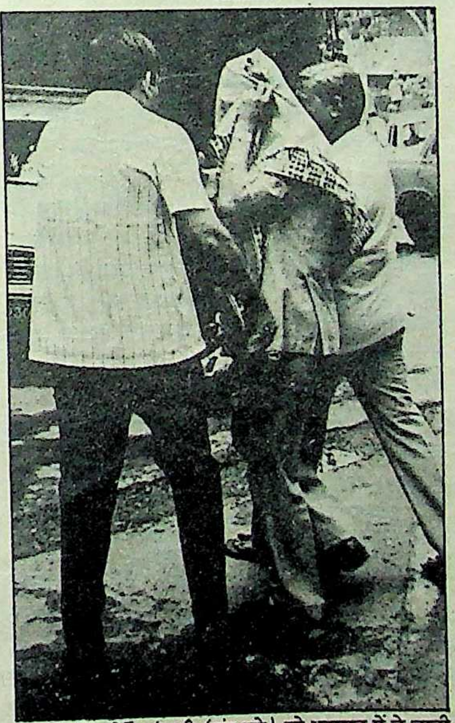

कठघरे में: कीर्ति अंबानी (मुंह ढके) को अदालत में ले जाती पुलिस

खुफिया पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने जिन सबूतों को कब्जे में लिया है, उनसे पता चलता है कि अभियुक्त बिना प्रमाण छोड़े इस ढंग से हमला करने की योजना बना रहे थे, ताकि वार खाली न जाये। वाडिया मध्य बंबई में प्रभादेवी में रहते हैं। वे दक्षिण-बंबई में बेलार्ड स्टेट कार्यालय तक कार से जाते हैं। दोनों स्थान समुद्र के निकट हैं। करीब १२ किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए निरंतर व्यस्त इलाके के जन सागर के बीच होकर जाना पड़ता है। कुछ ऐसे बड़े सिग्नल हैं, जिन्हें पार करने में २-३ मिनट तक रुकना पड़ता है।

पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने यह जानकारी जमा की थी कि वे घर से कब निकलते हैं तथा दोनों ओर से आने-जाने में कितना समय लगता है। कहा तो यहां तक जाता है कि १६ जुलाई से ३१ जुलाई के बीच पुलिस ने कई बार वाडिया की गाड़ी की नंबर प्लेट बदली तथा उनके वाहन से हर सिग्नल पर रुककर संभावित हमलावरों को ताड़ने की कोशिश की।

लेकिन कीर्ति अंबानी के वकील देसाई ने पुलिस के दावे को खोखला बताया और कहा, ''सिर्फ शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।'' उन्होंने अदालत में कहा कि यह मामला 'राजनीतिक रंग' लिये हुए है। देसाई के अलावा रिलायंस की तरफ से जो दो बयान जारी किये गये, वे भी गंभीर हैं। पहले बयान में तो यह कहा गया, ''रिलायंस की शोहरत से चिढ़कर जानबूझकर एक महाप्रबंधक को फंसाया जा रहा है। हमारा कर्मचारी निर्दोष है, उसे नाहक सताने के लिए ऐसा किया गया है। रिलायंस कंपनी जल्दी ही कारपोरेट क्षेत्र का बहुत बड़ा पब्लिक इशू जारी करने वाली थी। इसलिए उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।'' दूसरे बयान में सफायी दी गयी; ''कीर्ति, धीरूभाई अंबानी के रिश्तेदार नहीं हैं तथा धीरूभाई लंदन में इलाज करा रहे हैं।''

सीबीआई को क्यों?: बंबई के नामी पुलिस आयुक्त सराफ

सीबीआई का प्रवेश: अब सवाल यह है कि यह मामला सीबीआई को क्यों सौंपा गया? इस बात को लेकर काफी विवाद है, क्योंकि बंबई पुलिस छानबीन में काफी माहिर है और पुलिस आयुक्त वसंत सराफ और अतिरिक्त आयुक्त अरविंद इनामदार की

बदलते रिश्ते

बंबई पुलिस का दावा है कि कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार करने से पहले 'राज्य के सर्वोच्च स्थान' से अनुमति ले ली गयी थी। लेकिन पुलिस यह नहीं जानती कि राज्य के 'सर्वोच्च व्यक्ति' ने देश के 'सर्वोच्च व्यक्ति के आंख-कानों' से अनुमति ले ली थी या नहीं?

रिलायंस समूह ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि संगठन को जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने 'जानबूझकर' फंसाने की कोशिश की है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति तो शरद पवार में निहित है, लेकिन क्या शरद पवार इतने नासमझ हैं कि वे नहीं जानते कि अंबानी की पहुंच उस सत्ता-स्रोत तक है जो पवार को मिनटों में बना और मिटाने की क्षमता रखता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के राजनीतिक संरक्षक ने यह देखकर तटस्थता अपना ली हो कि अब और संरक्षण देने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? इन सवालों का उत्तर तो भविष्य ही देगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि देश की अनौपचारिक सत्ता को इस मामले में अवश्य तटस्थ होना चाहिए—कम-से-कम चुनाव के समय तक। सीबीआई की छानबीन चलती रह सकती है, लेकिन अदालती प्रक्रिया इतनी तेज नहीं हो सकती कि चुनाव के पहले कोई अंतिम फैसला हो जाये।

वाडिया और अंबानी दोनों ही औद्योगिक महारथी हैं, दोनों का युद्ध भी जग जाहिर है और दोनों की राजनीतिक पहुंच भी सर्वविदित है। इसलिए इनसे संबंधित हर घटना अपना महत्व रखती है। इस संदर्भ में 'दोनों की दोस्ती' की कहानी काफी अर्थगर्भित है। सभी जानते हैं कि दोनों के बीच 'पीटीए' और 'डीएलटी' रसायनों को लेकर घनघोर युद्ध हो चुका है। इसलिए जब यह पता चला कि संकट के समय रिलायंस ने बांबे डाइंग को रसायन बेचा है, तो इसे खबरनवीसों ने काफी महत्व दिया। क्या इस कथित दोस्ती ने सारे समीकरण बदल दिये? क्या यही कारण था कि अचानक वाडिया को भारत छोड़ने का फरमान थमा दिया गया? भारत में ऐसे हजारों व्यापारी हैं जो अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं, व्यापार कर रहे हैं और भारत में जहां, जब चाहा रहते आ रहे हैं। अकेले वाडिया को ही भारत में रहने के लिए अदालत की शरण में क्यों जाना पड़ा? क्या इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार में वाडिया के काफी बड़े विरोधी हैं? क्या इस मामले में देश के प्रधानमंत्री तटस्थ हैं? या किसी शकुनि ने धीरे से याद दिला दिया कि ये वही वाडिया हैं जिनकी दोस्ती हर्शमैन से है? हर्शमैन से राजनीति जुड़ी है और वाडिया का भी राजनीतीकरण हो चुका है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने राजनीतिक संरक्षण से अपराजेय औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है।

महाराष्ट्र सरकार सड़क निर्माण का ठेका निजी क्षेत्र को देना चाहती है। रिलायंस ने बांबे-यूरान अर्बन संपर्क सड़कों के लिए पहली बोली २२०० करोड़ रुपए की लगायी। अब 'बिजनिस इंडिया' का कहना है कि नये प्रस्ताव में रिलायंस के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एचसीसी) को भी जोड़ दिया गया है। एचसीसी के अजीत गुलाबचंद शरद पवार के पुराने दोस्त कहे जाते हैं।

बताया जाता है कि रिलायंस को 'यूरान पनवेल' पट्टी में ५० से ६० वर्ग किलोमीटर जमीन दी जायेगी, जिसे अच्छी सड़कों से जोड़कर विकसित किया जायेगा। जाहिर है, इसके बाद जमीन की कीमतें आसमान छूयेंगी।

यह भी बताया जाता है कि रिलायंस ने बांबे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (बीएसईएस) के १८ प्रतिशत शेयर खरीद लिये हैं। बीएसईएस उपनगरीय बंबई को बिजली प्रदान करता है। इस संस्थान के अधिकांश शेयर सार्वजनिक वित्त संस्थानों के पास हैं। अफवाह है कि केंद्र निकट भविष्य में वित्त संस्थानों से कहेगा कि वे अपने शेयर रिलायंस को बेच दें।

इन दोस्ती के सौदों के संदर्भ में देखें, तो आश्चर्य होता है कि 'राज्य की सर्वोच्च शक्ति' ने कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार करने के लिए बंबई-पुलिस को इजाजत कैसे दे दी?

◆

योग्यता और ईमानदारी की खासी धाक है। जाहिर है, बंबई पुलिस को भी यह बात नागवार गुजरी है कि मामला सीबीआई को दे दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसके मुखबिर सीबीआई को वे सूचनाएं देने में हिचकेंगे जो बंबई पुलिस को मिल सकती थीं। मुखबिर और पुलिस का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है और यह विश्वास अचानक नहीं जीता जाता। खबर यह भी उड़ी कि मामला सीबीआई को सौंपने से पहले ही सीबीआई के प्रमुख मोहन कात्रे बंबई पहुंच गये थे और अभियुक्तों को बंबई से दिल्ली ले आये थे। लेकिन चार अगस्त को सीबीआई के सूचना-अधिकारी भीष्म पाल ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि सीबीआई के निदेशक निजी तौर पर ऐसे मामलों में नहीं पड़ते।

यदि खबरों पर विश्वास किया जाये, तो राज्यपाल ब्रह्मानंद रेड्डी ने २ अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच ब्यूरो से छानबीन कराने के लिए कहा था। बताया जाता है कि उन्होंने एक अगस्त को ही राज्य सरकार के विरोध के बावजूद यह संकेत दिया था कि सीबीआई ही इसकी जांच करेगी।

राजनीतिक रंग: कीर्ति अंबानी के वकील कृष्णकांत देसाई ने अदालत में कहा था कि केस राजनीतिक रंग लिये हुए है। इस राजनीतिक रंग को उन्होंने विशद नहीं किया, परंतु कहते हैं, मुख्यमंत्री शरद पवार के बजाय राज्यपाल द्वारा कथित पत्र लिखने से मामले ने नया मोड़ लिया है। कुछ लोगों की यह राय भी है कि ऐसे संवेदनशील मामले को मुख्यमंत्री अपने अधीन नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है। दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अंबानी से नाखुश थे।

एक बड़े नेता ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री पवार के दाहिने हाथ माने जाने वाले अरविंद कुलकर्णी ने राज्यसभा में अंबानी पर जमकर हल्ला बोला था। क्या पवार अंबानी के पर काटना चाहते थे, क्योंकि वे अंबानी और उनके बेटे अनिल तथा मुकेश की राजीव गांधी से सीधी मुलाकातों को पसंद नहीं करते थे?

उल्लेखनीय है कि कीर्ति अंबानी के यहां पुलिस को मिले आपत्तिजनक सबूतों के बावजूद यह उजागर नहीं हो पाया है कि हत्या की साजिश के पीछे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के सिवा और क्या कारण हैं? क्या वाडिया के कब्जे में कुछ ऐसे सबूत हैं, जिनसे रिलायंस का साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है? हां, तो किस मामले में? यह तो नस्ली वाडिया ही बतला सकते हैं, जो प्रेस तो प्रेस, प्रेस-फोटोग्राफरों से भी कन्नी काट जाते हैं।

यह निश्चित है कि इस मामले से कांग्रेस के भीतर अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गये हैं। पूरा केंद्रीय (महाराष्ट्र का भी) मंत्रिमंडल अंबानी समर्थक तथा विरोधी खेमों में बंट गया है। खबरें यह भी हैं कि इंका सांसद भी दो खेमों में बंट गये हैं और प्रधानमंत्री के निकट सलाहकार भी इस मामले में विभाजित हैं। कीर्ति अंबानी के वकील ने एक और सवाल पूछा था, "अगर यह साजिश थी, तो नवंबर '८८ में साजिश रचने के बावजूद उसे अब तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया?" खुफिया पुलिस जांच के सबूतों के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त अरविंद इनामदार ने 'माया' से दावा किया, "हमारे पास सौ फीसदी पक्के प्रमाण हैं। जल्दी ही सामने आयेंगे।"

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने खतरा भांपने के बावजूद जांच की पहल की। यदि यह मामला भी संजय सिंह (सैयद मोदी हत्या कांड) की तरह रहा, तो जांच ब्यूरो की छवि मार खायेगी। यदि कीर्ति अंबानी छूटे, तो धारणा यही बनेगी कि बंबई पुलिस के किये-धरे पर पानी फेर दिया गया।

क्या नस्ली वाडिया, रामनाथ गोयनका तथा शरद पवार की तिकड़ी राजीव गांधी के खिलाफ खतरनाक सबूत दबाये है? क्या इसका विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस छोड़ो अपील से कोई संबंध है? ऐसे अनेक सवाल हैं, जिनका उत्तर समय ही देगा।

—बंबई ब्यूरो

TSA-C/DMHV/189/HN

ाज्य बढ़ा

ा का ठेका
स ने बांबे
हली बोली
'बिजनिस
रिलायंस के
ारपोरेशन
एचसीसी
राने दोस्त

को 'यूरान
टर जमीन
जोड़कर
इसके बाद

यंस ने बांबे
) के १८
ीएसईएस
ता है। इस
निक वित्त
केंद्र निकट
वे अपने

देखें, तो
शक्ति' ने
नए बंबई-

◆

ल अंबानी
। खबरें यह
गये हैं और
मामले में
ने एक और
, तो नवंबर
अब तक
किया पुलिस
त आयुक्त
या, "हमारे
ही सामने

के बावजूद
संजय सिंह
, तो जांच
बानी छूटे,
किये-धरे

नका तथा
के खिलाफ
विश्वनाथ
कोई संबंध
समय ही

बई ब्यूरो

"अपने डॉक्टर से यह जानकर
मुझे बड़ी खुशी हुई कि
केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र
से सचमुच बालों का
झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ
जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Dey's

TSA-C/DMHV/189/HN

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश :

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने और रूसी खत्म करने का
प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® देे'ज़ मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

* यह शृंगार सामग्री नहीं है।

मध्य प्रदेश का कुन्डम गाँव। शाम ढले, जब पंछी अपने नीड़ की ओर लौटते हैं, सुशीलाबाई भी अपने कर्मवीर पति की वापसी की राह देखती हुई अपनी नन्हीं-मुन्नी रजनी को बहलाती है। उसका नन्हा बेटा बलराम भी गौओं के साथ खेलता-कूदता लौटने वाला है। नन्हीं रजनी की किलकारियाँ उसे उस वक्त की याद दिलाती है...आज से ९ साल पहले जब उनका नया-नया ब्याह हुआ था और उन्होंने परिवार कल्याण के लिए नियोजन का संकल्प लिया था, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल रहे। आई टी सी ने उन्हें राह दिखायी...

कुन्डम की सुशीलाबाई। नये ब्याह के हुलास के साथ इन्हें चिन्ता थी कि इनकी नियति छः बच्चों के बोझ से थकी-टूटी इनकी माँ जैसी न हो।

तभी आई टी सी के माध्यम से इनके पति ने परिवार नियोजन साधनों को अपनाया।

आई टी सी भारत के गाँवों में निरोध साधनों की वितरक।

सन् १९६८ से आई टी सी भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी विशाल वितरण व्यवस्था और मार्केटिंग तजुर्बों के माध्यम से उन विस्तृत इलाकों में निरोध साधनों का प्रचार-प्रसार कर रही है, जहाँ देश की लगभग आधी आबादी बसी है।

सन् १९८९-९० में यह कंपनी जन शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम और निरोध साधनों के प्रचार योजना पर १ करोड़ से भी ज्यादा रुपये खर्च करेगी। सरकार के फैमिली-प्लानिंग विभाग के साथ कार्यरत आई टी सी की क्षेत्र-शक्ति प्राचीन रूढ़िवादी अंधविश्वासों के उन्मूलन, मातृत्व को प्रोत्साहन और शिशु-स्वास्थ्य देखभाल में मदद कर रही है। देश भर में निरोध साधनों की सबसे बड़ी वितरक के रूप में आई टी सी के अथक प्रयासों को समुचित इनाम भी मिला है—परिवार कल्याण के क्षेत्र में सन् १९८८ का एफ आई सी सी आई पुरस्कार। यह एक ऐसे सम्मान का प्रतीक है, जो सैकड़ों-हजारों परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य और खुशहाली का संदेश देता है।

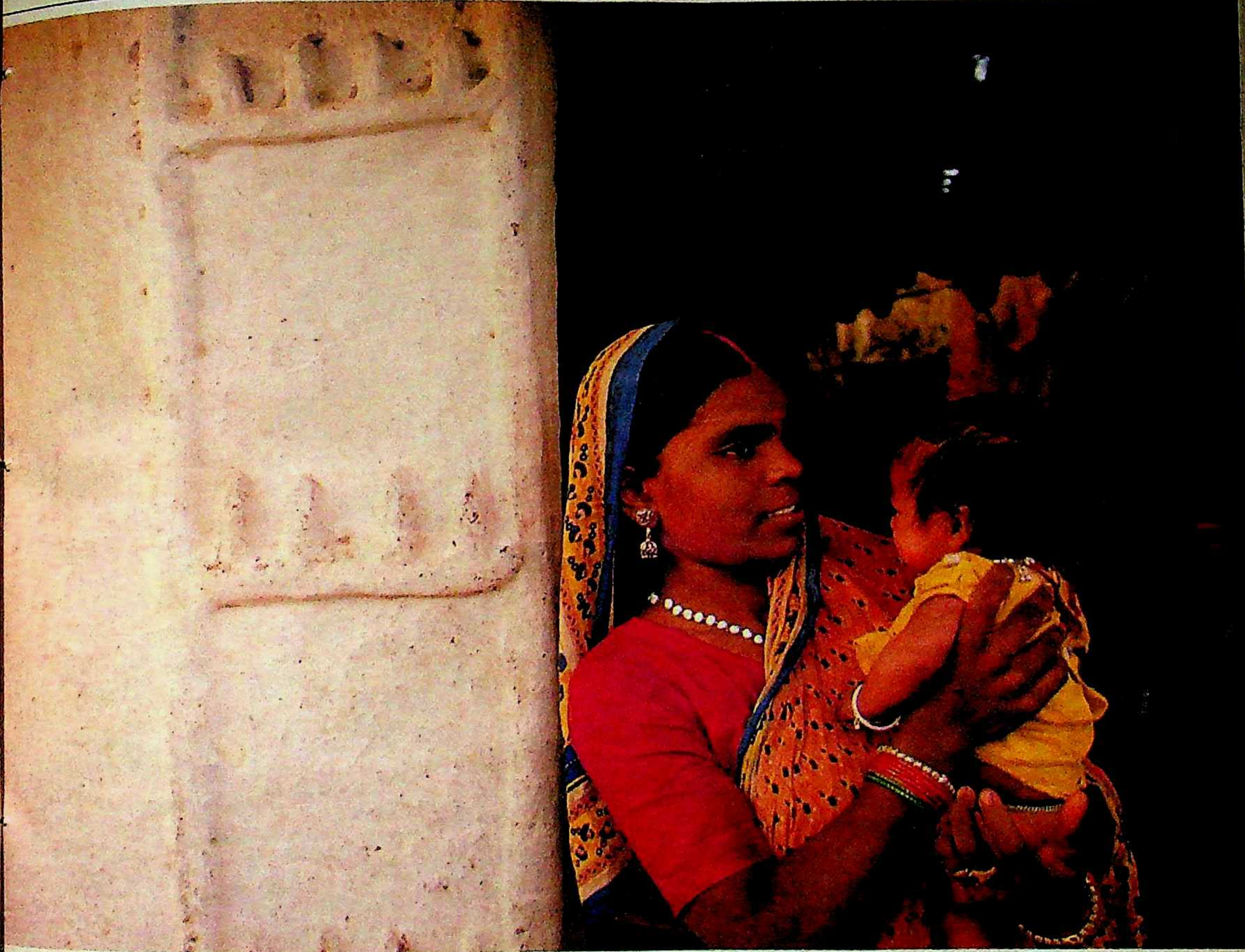

आई टी सी भारत के लिए और कहाँ-कहाँ कार्यरत है?

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी। खाद्य-अखाद्य तेलों एवं सहायक उत्पादनों के निर्माण और मार्केटिंग के साथ-साथ, आई टी सी ने आयात भी कम किया है।

कुटीर उद्योग : हथकर्घे, कच्चे माल और तकनीकी विशिष्टताओं के दम पर आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के जरिये शाहजहांपुर की प्राचीन कालीन-बुनाई कला को पुर्नजीवित किया है। अब कालीनों के साथ-साथ अन्यान्य लघु और कुटीर उद्योगों की सामग्रियाँ भी आई टी सी द्वारा निर्यात की जाती हैं।

पेपर और बोर्ड — कोर सैक्टर में : आई टी सी द्वारा विकसित भद्राचलम पेपरबोर्ड्स अपने क्षेत्र में अग्रणी है। इसने रिकॉर्ड उत्पादकता के साथ साथ वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी कल्याण के प्रति गहरी जागरूकता का नया मानदंड स्थापित किया है।

I.T.C. Limited

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

Contract. ITC. 58.89 HIN

संस्कृति के प्रति अपाहिज मानसिकता

राजस्थान का पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोक कलाकारों का उपयोग करने लगा है। पर उपयोग की यह निगाह निम्न तबकों से आये लोक कलाकारों को दैनिक मजदूरी पानेवाले श्रमिकों से ज्यादा तरजीह नहीं देती। इसकी ताजा मिसाल कालबेलिया (संपेरा) आदिवासी जाति की लड़की वसंती है।

पर्यटन विभाग इस जाति के कलाकारों के ग्रुप बना कर उनसे रोजनदारी पर काम लेता है। ग्रुप के गाने-बजाने और नाचनेवाले हर कलाकार को सौ रुपए रोज दिये जाते हैं। इस तरह महीने में दो-चार कार्यक्रम हर ग्रुप को मिल जाते हैं। पर्यटन विभाग ने वसंती व उसकी पार्टी को पिछले दिनों सवाई माधोपुर जिले के श्रीमहावीरजी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए बुक किया था। विभाग की बस से १८ अप्रैल को जब वह अन्य लोक कलाकारों के साथ श्रीमहावीरजी जा रही थी, तभी हिडौन के पास सामने से आती हुई राजस्थान पथ परिवहन की बस उनकी बस से टकरायी। परिणामस्वरूप छह लोक कलाकार घायल हुए। वसंती का बायां हाथ इतना जख्मी हुआ कि जयपुर लाने पर डाक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए बांह के पास से हाथ काटना पड़ा।

सामान्य वार्ड में भरती लोक कलाकारों की सुध लेने २१ अप्रैल को कला एवं संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती बीना काक अस्पताल पहुंचीं। वसंती को ढाई हजार रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान करने की घोषणा हुई। कलामंत्री के बाद २७ अप्रैल को पर्यटन राज्यमंत्री कुमारी गिरिजा व्यास ने वसंती का हाल देखा और सरकार की ओर से कृत्रिम हाथ लगाने का आश्वासन दिया। पर्यटन राज्यमंत्री ने महसूस किया कि अंगहीन वसंती अब नृत्य से अपना जीवन-यापन नहीं कर सकेगी, इसलिए सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। अस्पताल से निकलने के बाद वसंती ने कला एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त को नौकरी के लिए आवेदन किया, तो उसे ज्ञात हुआ कि वह बालिग नजर नहीं आती। उसके पिता कालूनाथ से कहा गया कि वसंती का आयु प्रमाणपत्र पेश करें। जो परिवार कल तक गली-महल्लों में गा-बजाकर पेट भरते थे, उनसे आयु प्रमाणपत्र की मांग कागजों में तो ठीक लगती है, लेकिन यथार्थ में यह अपेक्षा हास्यास्पद है। बहरहाल, सबूत के तौर पर जन्मपत्री पेश की गयी जिसे विभाग ने नहीं स्वीकारा।

छाया: प्रताप सिंह

विकलांगता की व्यथा: बांह कटने से बेसहारा वसंती

बेकार वसंती ने पर्यटन राज्यमंत्री गिरिजा व्यास को टटोला। उन्होंने नौकरी से पहले हाथ लगवाने वसंती को विभाग के एक अधिकारी के साथ पूना भेजा। आदेश दिया गया था कि वसंती को उसके पिता और छोटी बहन सोवत के साथ पूना ले जाना है। जयपुर से वसंती परिवार अधिकारी के साथ रवाना हुआ, तो अधिकारी ने उन्हें खाने के लिए बीस रुपए प्रतिदिन दिये। पूना पहुंचकर वापस लौटने तक बसंती और उसके परिवार के चांदी के गहने पेट भरने के लिए बिक चुके थे। बहरहाल, नकली हाथ मिलने की गारंटी वसंटी को मिल गयी है, लेकिन जीवन-यापन का कोई साधन इस परिवार के पास अब नहीं है। नौकरी देने की औपचारिकता पूरी करने में दोनों मंत्री भी नियमकायदों से परे जाने का हौसला नहीं जुटा पा रही हैं।

दास्तान से जाहिर है कि वसंती की बांह कटने और तबाह होने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर जाती है—जरिया चाहे पर्यटन विभाग हो या परिवहन विभाग। यह भी जाहिर है कि राज्य सरकार इस बेसहारा लोक संस्कृतिकर्मी किशोरी को जीने का साधन देने में पूर्णतः सक्षम है, लेकिन सरकार अपना फर्ज निभाना चाहे तब न! दुर्घटना से विकलांग वसंती को पथ परिवहन निगम से मुआवजा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कागजी कार्यवाही करने में वसंती असमर्थ है। वहीं पर्यटन विभाग गैरजिम्मेवार बना हुआ है।

लोक संस्कृति और लोक कलाकारों के लिए जो चाव राजीव सरकार में पैदा हुआ, उसका नतीजा है कि जयपुर की सड़कों पर नाचनेवाली गुलाबो अंतरराष्ट्रीय स्टार बन गयी। उसने वक्त के साथ-साथ मोल-भाव भी सीख लिया। तंबू-डेरों में रहते हुए अपनी हैसियत को भी पहचान लिया है। पर सामान्य कलाकार समूहों को आज भी काम के लिए विभाग के अफसरों को 'खुश-करना' पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सफेद चमड़ीवाले उन्हें भले ही सम्मान देते हों, पर काली चमड़ीवाले साहब लोग आज भी उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे सड़क पर हाथ फैलाने के वक्त देखा करते थे।

आज वसंती का हाथ कट गया है। कल गुलाबो की उम्र ढल जायेगी। तब की स्थितियों में इन लोक कलाकारों का क्या होगा? इस पर लोक संस्कृति विभाग ने विचार नहीं किया है। इसीलिए इन समुदायों को नये आधार और आर्थिक संबल के स्रोत प्रदान करने की दिशा में सर्वेक्षण, योजनाएं एवं उपायों का रास्ता उसने अब तक नहीं अपनाया। उसे चंद पर्यटक-स्थलों, मेलों, उत्सवों में इन्हें सजा-संवार कर पेश करने से ही मतलब है, लोक परंपरा को जीवित रखने से नहीं।

—ओम सैनी

जमाने के साथ: गुलाबो

छाया: प्रताप सिंह

Rashmi
ZAFRANI PATTI
Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
SATYAPAL SHIVKUMAR
355 NAYA BANS DELHI-110006 (INDIA)
BLISS/DEL

पेश हैं जनाब एक स्वाद लाजवाब,

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद,
वाह! क्या लाजबाब.......

रश्मि ज़र्दा

सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006

(वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

१९७२ के बाद पहली बार : बंबई में मची तबाही का एक दृश्य

समुद्र के रास्ते आयी तबाही

यदि भारत का मौसम विभाग समय पर सूचना दे देता, तो २४ जुलाई को बंगाल की खाड़ी से उठे भयानक चक्रवात से भारत के दक्षिण-पश्चिमी सागर तटवर्ती इलाकों में हुई जन-धन की भीषण हानि को कम किया जा सकता था। तब मछुआरों की ३०० नौकाएं खुले समुद्र में निकल कर लापता नहीं होतीं और खासकर बंबई को तबाही का इतना भीषण कहर न भुगतना पड़ता। सवाल यह है कि मौसम विभाग उसी दिन नकारा क्यों साबित होता है, जिस दिन के लिए उसे करोड़ों रुपए के खर्चे पर पाला पोसा जा रहा है?

२२-२३ जुलाई '८९ को बंगाल की खाड़ी में बढ़ते दबाव ने २४ जुलाई की भोर में अचानक भयावह रूप ले लिया। ७० से १२५ किमी वेग से आये तूफानी चक्रवात ने दक्षिण-पश्चिम सागर तटों पर बसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा तथा केरल को अपनी लपेट में लेकर भीषण तबाही पैदा कर दी। चक्रवात के कहर का सबसे बड़ा शिकार हुआ महाराष्ट्र, जहां अपुष्ट समाचारों के अनुसार ७५० से १००० व्यक्तियों (सरकारी सूचना के अनुसार सिर्फ ३५७, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक) को अकाल मौत का शिकार होना पड़ा। इसमें सर्वाधिक विनाश का शिकार हुआ महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, जहां मरनेवालों की संख्या (३०० से अधिक, सरकारी सूचना के अनुसार २००) अभी सही ज्ञात नहीं हो सकी है। अभी भी लाशें निकाली जा रही हैं। रायगढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुसेना के हेलीकाप्टरों ने ५ टन से ज्यादा खाद्य सामग्री के पैकेट गिराये लेकिन ६० प्रतिशत सामग्री ही उन तक पहुंच सकी। या तो पैकेट दलदल या बाढ़ के पानी में गिर गये अथवा जमीन से टकरा कर फूट गये।

भयावह चक्रवात के फलस्वरूप रायगढ़, लातूर, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सतारा, चालीसगांव, जांगली, सांगली, बुलढाणा, नांदेड, परमाणी, बीड, पुणे, ठाणे आदि डेढ़ दर्जन से अधिक महाराष्ट्र के जिलों की अधिकांश नदियों में बाढ़, जलप्लावन, जमीन धसकने तथा बांधों के टूटने के कारण अनगिनत व्यक्ति, पशु, घर, सड़कों पर खड़े वाहन बह, मर या लापता हो

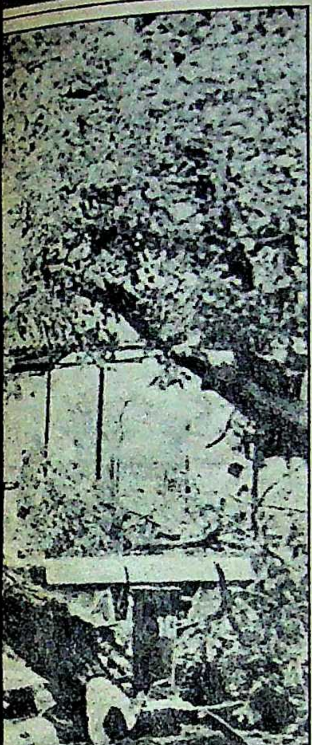

छाया: श्रीराम बरनेकर

गये। पुणे में माजे नामक गांव में जमीन धसकने से ३८ व्यक्ति जिंदा दफन हो गये, पानशेत बांध के टूट जाने के कारण भी भारी तबाही हुई, जो १९६१ की भीषणतम तबाही से अधिक भयंकर थी। लोनावाला के निकट कामशेत-वड़गांव के बीच पुल टूट जाने से एक ट्रेन की दो बोगियां नदी में जा गिरीं और ८ से अधिक व्यक्तियों ने जल-समाधि ले ली। बंबई से पुणे होकर दक्षिण भारत की तरफ जानेवाली ट्रेनें कई दिनों तक रद्द हो जाने के कारण दक्षिण से यातायात संपर्क भंग हो गया। वाकन नाका के निकट एक स्कूल में मौजूद ३६ विद्यार्थी एक शिक्षक सहित बह गये।

बंबई तथा निकटवर्ती समुद्री तटों से मछली मारने के लिए गयी ३०० से अधिक मच्छीमार नौकाओं में सवार लगभग ढाई हजार मछुआरे लापता हो गये। चक्रवात में फंसे एक मछुवारे अशोक बाबाजी श्रीगांवकर ने सुरक्षित वापस आने पर 'माया' को बतलाया, "हमेशा की तरह हम मच्छी मारने के लिए कस्टम विभाग से अनुमति पर्ची लेकर (मछुवारों को समुद्र में जाने से पहले कस्टम विभाग का परमिट लेना जरूरी होता है) अपने साथियों के साथ अपनी नौका 'आई भवानी' में सवार हो कर गये। अचानक चक्रवात में हम फंस गये, साथियों का क्या हुआ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी नौका से चिपट गया और तूफानी लहरों के थपेड़े सहता रहा। मुझे पता नहीं कब दूसरी नौका के लोगों ने मुझे बचाया। हमारे साथ गयी दूसरी मच्छीमार नौकाओं के मछुआरों का क्या हुआ, पता नहीं। हमें मौसम विभाग ने भी चक्रवात आने की कोई चेतावनी नहीं दी थी।"

चेतावनी का दावा: कोलाबा स्थित वेधशाला के एक अधिकारी केके चक्रवर्ती का कहना था—"हमने चक्रवात के कहर बरपाने की चेतावनी पहले ही आकाशवाणी समेत बंबई महानगर निगम, बंदरगाहों, सिंचाई, रेलवे आदि सरकारी दफ़्तरों को दे दी थी। आकाशवाणी से इस बात का अनुरोध भी किया कि इस सूचना को वे कम-से-कम चार बार अवश्य प्रसारित करें। मछली विभाग के भी सभी दफ्तरों को इस बारे में सूचित कर दिया गया था, अब यह उनका काम था कि वे इसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाते।" लेकिन एक अन्य सरकारी अधिकारी ने इसे गलत बतलाया, "अगर हमें या संबंधित विभागों को बंगाल की खाड़ी में दबाव बनते ही सूचित कर दिया गया होता, तो इस दर्दनाक हादसे से बचने के लिए जरूरी कदम तुरंत उठा लिया जाता और इतना अधिक नुकसान तथा मौतें नहीं हो पातीं।" मछुआरों की शिकायत थी कि चक्रवात में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए नौसेना, राज्य सरकार तथा तटरक्षकों की ओर से कोई विशेष कारगर कार्रवाई नहीं की गयी। अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति के महासचिव दामोदर तांडेल का कहना था कि उन्होंने मुरुड-जंजीरा (हीरा-रत्ना तेल क्षेत्र) के पास फंसी २०० नौकाओं को बचाने के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर एचएन शिरगावी को पत्र लिखा था। अगर मौसम विभाग ने ही सही समय पर सूचना दे दी होती, तो इस प्रकार मछुआरों की मौतें नहीं होतीं। २४ जुलाई को सुबह कस्टम अधिकारियों ने हमेशा की तरह मछुआरों को नौकाएं ले जाने के लिए अनुमति पत्र जारी किये थे, निश्चय ही उन्हें भी चक्रवात आने की सूचना नहीं थी।

रायगढ़ के पीड़ित ग्रामीणों ने भी सरकारी लापरवाही की शिकायत की कि कोई भी सरकारी संस्था उनकी सहायता के लिए, चक्रवात आने के बाद ७० घंटों तक, आगे नहीं आयी। मौजूद पुलिसजन कलेक्टर के आदेश की प्रतीक्षा में हाथ बांधे निष्क्रिय खड़े रहे।

चक्रवात ने बंबई महानगर को भी बुरी तरह से तबाह किया, जिसके फलस्वरूप पूरे एक सप्ताह से अधिक समय तक लोकल तथा बंबई से बाहर जानेवाली ट्रेन सेवाएं अस्तव्यस्त हो गयीं। यों बंबई में हर वर्ष मानसून के मौसम में लोकल ट्रेनों का ठप हो जाना आम बात है, लेकिन १९७२ (जब बंबई में आये तूफानी चक्रवात ने १२० वर्षों का कीर्तिमान भंग किया था) के बाद पहली बार इतना भीषण कहर बंबई को भुगतना पड़ा। रेलवे अधिकारियों तथा परिवहन विभाग ने १९७२ के तूफानी चक्रवात से सबक लेकर ऐसी स्थिति से निबटने का इंतजाम नहीं किया। बाहर से आनेवाली ट्रेनें तथा बंबई की लोकल ट्रेनें ३० घंटे तक जहां थीं, वहीं खड़ी रह गयीं। तूफानी हवा के कारण कार-बसों के रुख तक किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर बदल गये। अपुष्ट समाचारों के अुसार बंबई में लगभग १०० (सरकारी सूचना के अनुसार ५०) लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। बंबई का संपर्क पूरे देश से दो दिनों से अधिक समय तक कटा रहा। निचले क्षेत्र जलमग्न तथा बाढ़ की चपेट में आ गये। पानी में डूबी रेलवे लाइनें, जलमग्न बस्तियां तथा सड़कों पर जड़ समेत उखड़े भारी वृक्षों के नीचे चकनाचूर हजारों कारों-मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का दृश्य आम था।

पातालगंगा नदी में बाढ़ के कारण वहां की औद्योगिक इकाइयों को सर्वाधिक नुकसान होने के कारण कपड़ा उद्योग संकट में पड़ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०, ओरके, बांबे डाइंग, हिंदुस्तान आर्गेनिक के अलावा एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम) की ८० प्रतिशत इकाइयां नेस्तनाबूद होने की हालत में आ गयीं।

आंध्र प्रदेश: महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक विभीषका आंध्र प्रदेश को भुगतनी पड़ी। पिछले एक दशक से तूफानी हवाओं, बारिश तथा बाढ़ का कहर हर वर्ष आंध्र प्रदेश को ग्रसता रहा है, लेकिन नये-नये बने विश्वामित्र उर्फ मुख्यमंत्री एनटी रामाराव इससे निबटने का कोई सार्थक हल नहीं तलाश पाये हैं। सर्वाधिक नुकसान कृष्णा, विजयावाड़ा तथा निडावोल जिलों को हुआ। ये क्षेत्र बाढ़ के पानी से घिर गये। इन क्षेत्रों के लोगों सहित मछुआरों को अपनी नौकाएं ट्रकों में लादकर सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए विवश होना पड़ा।

मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने केंद्र पर यह आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने की कोशिश की कि केंद्र इन निचले तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दे रहा है और भेदभाव बरत रहा है। देश के दक्षिणी क्षेत्रों में आये चक्रवात तथा बाढ़ के लिए सहायतार्थ केंद्र द्वारा मंजूर की गयी धनराशि के आवंटन में भी भेदभाव बरता जा रहा है।

कर्नाटक, केरल तथा गुजरात भी इस तूफानी बाढ़ की चपेट में हैं। केरल में १०० से अधिक व्यक्ति मौत के शिकार हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या मुन्नार की है, जहां एक लाख से अधिक लोग बाढ़ के पानी में घिर गये।

इस प्राकृतिक आपदा के लिए सरकारी तंत्र किस हद तक जिम्मेदार है, यह जगजाहिर है, लेकिन बंबई के ज्योतिषियों के अनुसार यह भीषण उत्पात मंगल-राहु के कारण हुआ। मंगल ग्रह की संक्रांति का अंतिम दिन होने तथा रात्रि में मंगल तथा राहु का नवम पंचम योग बनने के कारण तूफानी चक्रवात का कहर शुरू हुआ।

—बंबई ब्यूरो

टीवी उद्योग

उजले वर्तमान का धुंधलाता भविष्य

देश की लगभग ८७ प्रतिशत आबादी आगामी चुनाव तक टीवी की परिधि में आ जायेगी। जाहिर है, इससे टीवी की खपत बढ़नी चाहिए, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ **कुमारेश चक्रवर्ती** का आकलन है कि आगे चलकर टीवी उद्योग पर खतरा मंडराने वाला है। प्रस्तुत है, उनका विश्लेषण :

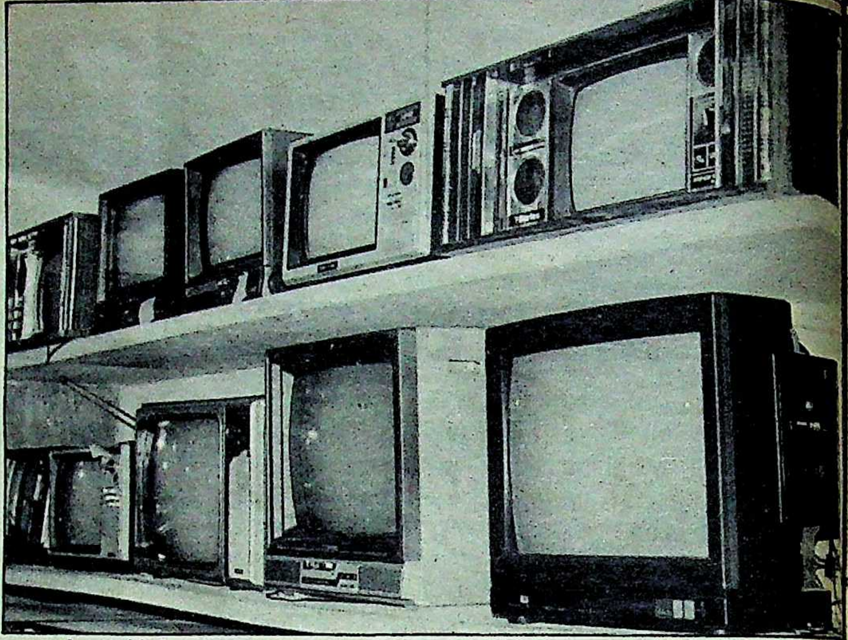

क्या खरीदार बढ़ेंगे ?

लगता है, दूरदर्शन उद्योग भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत से नगरों में टीवी विक्रेता किस्तों पर टीवी बेचने पर उतर आये हैं। इसके बावजूद भी ग्राहकों की भीड़ जुटती नहीं नजर आ रही है। हां, यह जरूर है कि १४ इंच परदेवाले ब्लैक एंड ह्वाइट टीवी की मांग अभी भी बाकी है जो २००० से २५०० रुपए के बीच उपलब्ध हो ही जाता है। दूसरी ओर रंगीन टीवी कंपनियों की हालत तो और भी खस्ता दिखायी पड़ रही है। इन कंपनियों के बीच अपने उत्पादन बेचने की ऐसी होड़ लगी है, कि कंपनियां भद्दे विज्ञापन-युद्ध के दौर में प्रवेश कर गयी हैं। जबकि असलियत यह है कि रंगीन टीवी बनानेवाली कुल ७९ कंपनियों में से सिर्फ १७ कंपनियां ही ऐसी हैं जो देश के रंगीन टीवी के ९० प्रतिशत बाजार पर छायी हुई हैं। शेष ६२ कंपनियों की हालत तो बड़ी चिंताजनक है।

अच्छे भविष्य की उम्मीद : कौन नहीं जानता कि ये कंपनियां अच्छे भविष्य की उम्मीद लेकर टीवी उत्पादन के क्षेत्र में आयी थीं, क्योंकि सरकार ने टीवी उत्पादकों को हर तरह का सहयोग तथा रियायत देने का वायदा किया था। यही नहीं, शुरू में विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी भी की थी कि टीवी सेटों की मांग देश में दिन-पर-दिन बढ़ती ही जायेगी। नतीजतन छोटी-बड़ी सैकड़ों कंपनियां अपनी हैसियत के हिसाब से अधिकतम उत्पादन क्षमता के साथ इस क्षेत्र में कूद पड़ीं।

किंतु आज स्थिति यह है कि उनमें से कुछ कंपनियां तो पूरी तरह बाजार से गायब हो गयी हैं। कुछेक तो नामवर कंपनियां थीं। साराभाई जैसे नामीगिरामी उद्योगपति समूह ने 'टेलीराड' नाम से बाजार में धूम मचायी थी, बिड़ला समूह 'कैनन' की खूबियों का बढ़-चढ़कर प्रचार कर रहा था, सिंघानिया 'जेके' टीवी को सबसे बेहतर बता रहे थे और एस्कार्ट्स के एचपी नंदा तो 'निकीताशा' की अंतरराष्ट्रीय छवि के साथ इस क्षेत्र में कूदे थे। किंतु आज इनमें से किसी की ब्रांड बाजार में देखने को नहीं मिलती जैसे ये नाम टीवी उत्पादन के इतिहास में गायब हो गये हों।

बात घूम-फिर कर दुबारा उसी तथ्य पर पहुंचती है कि इस क्षेत्र की होड़ और खस्ताहाली की जिम्मेदार सरकार ही है। जाहिर है, सरकार ने ही तो लोगों को इस ओर इस वायदे के साथ आकर्षित किया था कि निकट भविष्य में देश की कुल आबादी को प्रसारण सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसके लिए देश भर में विभिन्न हिस्सों में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र खोले जायेंगे। यही नहीं, सरकार ने समय-समय पर कर-छूट तथा अन्य रियायतों का भी वायदा किया था। किंतु क्या सरकार ने अपने वायदे पूरे किये ? और तो और जब १९८२ में 'एशियाड' का आयोजन हुआ, तो रंगीन प्रसारण के युग की शुरुआत हुई और देखते-ही-देखते रंगीन टीवी की मांग जोर पकड़ने लगी।

छलांग का दौर : इस बात में शक नहीं कि शुरू के दौर में टीवी सेटों की मांग छलांग लगा रही थी। यही वजह थी कि टीवी उत्पादन के लिए लाइसेंस चाहनेवालों की कतार लगने लगी थी। चूंकि रंगीन टीवी सेटों में जल्दी और ज्यादा लाभ की गुंजाइश थी, इसलिए बहुतेरी कंपनियों ने रंगीन टीवी के उत्पादन का काम शुरू किया। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि १९८२-८५ के बीच ब्लैक एंड ह्वाइट टीवी सेटों के उत्पादन में तो सिर्फ ढाई गुना ही उछाल आयी, किंतु रंगीन टीवी सेटों का उत्पादन ४ गुना बढ़ा।

इसके बाद ही पतन की शुरुआत हुई। १९८७-८८ में कंपनियों ने १३ लाख टीवी बनाये, किंतु १० लाख से ज्यादा टीवी बिक सके। (देखें बाक्स)। यानी ३ लाख टीवी बिक सके। जाहिर है, इतने सेटों के न बिकने के का लगभग २५० करोड़ रुपए तो घपले में पड़ ही होंगे। यही नहीं, यदि उपर्युक्त १० लाख टीवी की बिक्री का और विश्लेषण किया जाये, तो स्थिति सामने आयेगी वह और भी रोचक आंकड़ों के अनुसार कुल बिके १० लाख सेटों में लगभग साढ़े सात लाख सेट तो मात्र १७ कंपनियों ही थे। इन १७ कंपनियों में भी भाग्यशाली कंपनि केवल ७ ही थीं, जिनके सेट दूसरों के मुकाबले तादाद में बिके थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनु भाग्यशाली ७ कंपनियों ने मिलकर लगभग ६ टीवी सेट बेचे थे, जबकि शेष १० कंपनियों ने लगभग डेढ़ लाख सेटों में भागीदारी की। यानी कंपनियों ने औसतन लगभग १५००० टीवी बेचे। यहां पर इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है मात्र १५००० सेट बेचकर आवश्यक लाभ कमा संभव नहीं है। देश की शेष ६२ कंपनियों ने लग २ लाख टीवी बेचे, जिनके औसत से साफ जाहि होता है कि उनका इस क्षेत्र में ठहर पाना लोहे के चबाने के बराबर है।

लाभ घटा: आज तो स्थिति यह है कंपनियों को जो लाभ शुरू के दौर में हुआ, उ आधे की भी गुंजाइश नहीं बची है। इसकी एकम वजह बिक्री बढ़ाने के लिए जरूरी साधनों (विज्ञा आदि) का महंगा होना। विज्ञापन, जिसे बि बढ़ाने का बढ़िया साधन माना जाता है, वह जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया है। व्यापार ज्यादा-से-ज्यादा छूट देने की जो परंपरा चल पड़ी उसने भी लाभ घटाया है, क्योंकि फुटकर विक्रेता

को अधिक
इस बात प
कंपनी के
बेचने का
अव
का जायजा
की बिक्री ब
माल बढ़िय
जब कोई क
तो सामने
विज्ञापन-यु
में हाल के
किया जा
विज्ञापन
इकानामिक
करते हुए य
टीवी सेटों
बताने के f
कान की
वीडियोका

ब्रांड
बीपी
ओनी
डायन
क्राउ
बुश
वेस्टन
केल्ट्र
विदेश
अन्य
निम्न
कुल

नोट
रिपो

इसलि

नहीं थी।
प्रदीप कु
इकानामि
हम देखेंगे
हैं ?'' इस
विज्ञापन प्र
गया कि
टीवी सेटों
गलत हैं।
वीडियोक
इस विज्ञाप

को अधिक-से-अधिक लाभ तथा रियायतें देकर ही इस बात पर राजी किया जा सकता है कि वे अमुक कंपनी के सेट अपनी दुकान पर रखें तथा उन्हें ही बेचने का प्रयास करें।

अब आइये विज्ञापन के क्षेत्र में आये भूचाल का जायजा लें। स्थिति काफी गर्म है। अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए दूसरे से तुलना करके अपना माल बढ़िया बताने के दौर की शुरुआत हो चुकी है। जब कोई कंपनी किसी के माल को नीचा दिखाती है, तो सामने वाली चुप नहीं बैठती। नतीजतन भद्दे विज्ञापन-युद्ध का दौर चल पड़ता है। उदाहरण के रूप में हाल के बीपीएल-वीडियोकान के युद्ध को पेश किया जा सकता है। बीपीएल कंपनी ने एक विज्ञापन में नेशनल काउंसिल आफ एप्लाईड इकानामिक्स रिसर्च के सर्वेक्षण आंकड़ों का उल्लेख करते हुए यह दावा किया कि उसके बनाये हुए रंगीन टीवी सेटों की बिक्री सबसे ज्यादा है। किंतु यह बताने के लिए उसने यह भी कह डाला, "वीडियोकान की बिक्री महत्वपूर्ण नहीं है।" जाहिर है, वीडियोकान के लिए यह विज्ञापन कोई मामूली बात नहीं थी। वीडियोकान इंटरनेशनल के निदेशक प्रदीप कुमार धूत आगबबूला हो उठे और इकानामिक टाइम्स के संवाददाता से बोले, "अब हम देखेंगे कि बीपीएल के सेट बाजार में कैसे बिकते हैं?" इस खबर के साथ ही वीडियोकान का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बीपीएल के विज्ञापन में पांच कंपनियों के टीवी सेटों की बिक्री के जो आंकड़े पेश किये गये हैं, वे गलत हैं। असलियत तो यह है कि ८८-८९ में वीडियोकान के २ लाख से ज्यादा टीवी सेट बिके। इस विज्ञापन पर बीपीएल खामोश नहीं बैठी। उसने पुनः विज्ञापन देकर दावा किया कि उसने सर्वेक्षण के आधार पर जो आंकड़े पेश किये, वही सच हैं।

रंगीन टीवी की बाजार में भागीदारी

ब्रांड	प्रतिशत
बीपीएल	११.८३
ओनीडा	१०.८८
डायनोरा	९.९८
क्राउन	७.१७
बुश	५.३४
वेस्टन	४.४३
केल्ट्रान	४.४०
विदेशी ब्रांड	३.२९
अन्य ब्रांड	२१.५८
निम्न स्तर की ६२ ब्रांड	२१.१०
कुल बिक्री (लाख में)	१०.८१

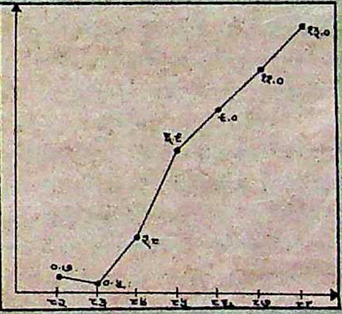

नोट: (१) उपर्युक्त तालिका नेशनल काउंसिल आफ एप्लाईड इकानामिक रिसर्च की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है।

(२) वीडियोकान का दावा है कि उसने १९८७-८८ में १,४०,००० टीवी सेट बेचे, इसलिए उसकी बाजार में भागीदारी को बीपीएल से अधिक माना जायें।

विज्ञापन युद्ध: इसी तरह विक्रेताओं को दी जानेवाली रियायतों ने भी नये-से-नये आयाम पकड़े हैं, जिससे कंपनियों को होनेवाला लाभ घटा है। एक कंपनी नें तो अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़ी आकर्षक योजना पेश की। कंपनी द्वारा निर्धारित मात्रा में टीवी सेट बेचने पर विदेश यात्रा, एक मारुति कार तथा शहर में सुसज्जित फ्लैट आदि का खुला प्रलोभन दिया गया है। जाहिर है, ऐसे में दूसरी कंपनियों के समक्ष सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता कि या तो वे भी इसी टक्कर की योजना बनाये अथवा इससे कुछ बेहतर घोषणा करके विक्रेताओं को आकर्षित करें। यह सब बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आने वाले दिनों में बाजार में यही परंपरा बढ़ती जायेगी तथा स्थिति यह हो जायेगी कि रंगीन टीवी बनानेवाली ७९ कंपनियों में से २० से ज्यादा बाजार में ठहर नहीं पायेंगी। वह बात और है कि अचानक टीवी सेटों की घरेलू मांग बढ़ जाये और कमजोर कंपनियां भी जीवित रहने के साजोसामान मुहैया कर बाजार में टिकी रहें। किंतु फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, उन्हें सामने रखते हुए इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या टीवी सेटों की मांग भविष्य में बढ़ेगी?

जहां तक टीवी सेटों की मांग बढ़ने का सवाल है, तो यह बताना जरूरी है कि मांग दो ही सूरतों में बढ़ सकती है। या तो परिवारों की आय में अब के मुकाबले बढ़ोतरी हो अथवा टीवी सेटों की कीमत इतनी घट जाये कि परिवारों को अपनी मौजूदा आय में भी टीवी खरीदना मुश्किल न लगे। यहां पर यह बताना जरूरी है कि कोई भी कंपनी कीमतों में भारी कमी करके जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि टीवी सेटों की बिक्री दर में विज्ञापन, व्यापार-रियायत, मरम्मत खर्च आदि शामिल हैं। फिर विज्ञापन आदि की जो मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए यह अनुमान लगाना भी गलत है कि आगे चलकर इन खर्चों में कटौती की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में टीवी सेटों की कीमत घटने की कल्पना उचित नहीं नजर आती। इसके अलावा सरकार की ओर से भी वायदे पूरे होते नहीं नजर आ रहे हैं। करों की जो स्थिति है, वह काफी चिंतनीय है। फिर मौजूदा बजट (८९-९०) में ही सरकार ने रंगीन टीवी सेटों पर जिस तरह से कर बढ़ाया है, उससे सरकारी नजरिये का पता चलता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उत्पादक सरकार को दोष तो देते हैं, किंतु अपने लाभ में कमी नहीं करते। मौजूदा बजट में जो अतिरिक्त 'कर' लगे उसका पूरा भार उपभोक्ता पर ही पड़ा, क्योंकि उत्पादकों ने अपने लाभ में कटौती नहीं की। ऐसे में मांग का घटना स्वाभाविक है।

आशावादी नजरिया: वैसे भारतीय टीवी उत्पादकों का संगठन आईटीएमए टीवी सेटों की मांग के संबंध में काफी आशावादी नजरिया पेश करता है। अपने इसी नजरिये के आधार पर उसने १९८८ की दरों के अनुसार १९९४-९५ तक की टीवी सेटों की मांग का लेखा-जोखा भी तैयार कर रखा है। जबकि टीवी सेटों की दरें १९८९ में बढ़ी हैं और कीमत में हुई बढ़ोतरी से ही मांग पर बुरा असर पड़ा है। हो सकता है, संगठन ने इस उम्मीद पर मांग बढ़ने की बात सोची हो कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार 'करों' में कटौती करेगी।

अब सवाल यह है कि टीवी सेटों की घरेलू मांग कितनी बढ़ेगी? आईटीएमए के आकलन के अनुसार १९९४-९५ तक १ करोड़ २० लाख टीवी सेटों की मांग बढ़ेगी, जो १९९०-९१ के बीच लगभग ७५ लाख रहेगी। यानी १९९०-९५ के पांच वर्षों के दौरान मांग १० प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ेगी।

टीवी उत्पादकों के संगठन ने आगामी वर्षों में टीवी सेटों की मांग में बढ़त का जो आकलन प्रस्तुत किया है, वह किसी हद तक गलत नहीं लगता, यदि ब्लैक एंड ह्वाइट टीवी सेटों की उत्पादन-बढ़त दर को सामने रखा जाये। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि १९८४-८८ के बीच ब्लैक एंड ह्वाईट टीवी सेटों की उत्पादन वृद्धि दर ४५ प्रतिशत तथा रंगीन टीवी सेटों की उत्पादन वृद्धि दर ४६ प्रतिशत थी। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि मांग शुरू के दौर में तो तेजी से बढ़ती है, किंतु बाद में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर शुरू के पांच सालों में, जब १९७० में टीवी का उत्पादन शुरू हुआ, टीवी सेटों की उत्पादन वृद्धि दर ४४ प्रतिशत थी, किंतु बाद में (७६-८०) उत्पादन वृद्धि दर घटकर २२ प्रतिशत हो गयी। इसी तरह रंगीन टीवी के उत्पादन की शुरुआत होने पर १९८१-८५ के बीच उत्पादन वृद्धि दर ५४ प्रतिशत थी। यानी इस दौरान कुल टीवी सेटों की

आईटीएमए का हिसाब कितना सही ?

व्यवसायियों के लिए जरूरी है कि वे अपने उत्पाद की भावी मांग का समय-समय पर आकलन करते रहें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए टीवी उत्पादकों के संगठन आईटीएमए ने तीन तरह के टीवी सेटों की भावी मांग का आकलन किया है, जिसमें १४ इंच परदेवाले ब्लैक एंड ह्वाइट, २० इंच ब्लैक एंड ह्वाइट तथा २० इंच रंगीन टीवी शामिल हैं। संगठन के हिसाब के अनुसार १९९०-९१ में ७५ लाख टीवी सेटों की मांग रहेगी तथा १९९४-९५ में यह मांग एक करोड़ २० लाख तक पहुंच जायेगी।

अनुमान क्या है ?: उल्लेखनीय है कि संगठन ने मांग का जो हिसाब प्रस्तुत किया है उसमें निर्यात, नयी मांग तथा प्रतिस्थापन (रीप्लेसमेंट) मांग शामिल है। यहां पर इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि जहां तक निर्यात मांग का आकलन करने का मामला है, यह मानकर चलना चाहिए कि अगले ५ अथवा १० साल के बाद अन्य देशों में मांग की जो स्थिति रहेगी इसका अंदाज लगाना आसान बात नहीं। फिर अंदाज लगाया भी किस आधार पर जाये ? ज्यादा-से-ज्यादा पिछले अनुभवों तथा परिस्थितियों को ही तो आधार बनाया जा सकता है। इस आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसे पूरी तरह सही कैसे माना जा सकता है ? फिर भी यदि पूर्व के अनुभवों को ही आधार बनाया जाये, तो कहा जा सकता है कि अगले ६ वर्षों में अधिकतम ५ से ६ लाख टीवी सेट प्रतिवर्ष ही निर्यात किये जा सकते हैं।

निर्यात मांग के बाद दूसरे नंबर पर है, प्रतिस्थापना मांग। आमतौर से प्रतिस्थापन की संभावना टीवी खरीदने के दस साल बाद ही बनती है, क्योंकि थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद कम-से-कम १० साल तो एक टीवी चल ही सकता है। ऐसे में १९८० में बने तथा बिके टीवी सेटों के प्रतिस्थापन का समय १९९० में आयेगा। यदि यह मान लिया जाये कि १९८४ में बने १२.७५ लाख टीवी सेटों में से ७५००० टीवी निर्यात हुए थे और १२ लाख देश में बिके थे, तो १९९४-९५ में लगभग १२ लाख टीवी सेटों का प्रतिस्थापन होगा। यानी १२ लाख टीवी सेटों की मांग बढ़ेगी। इस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुचा जा सकता है कि १९९४-९५ के बीच निर्यात तथा प्रतिस्थापन को मिलाकर १८ लाख टीवी सेटों की मांग होगी। यदि इस आंकडे को टीवी उत्पादकों के संगठन द्वारा दिये गये आंकड़े से मिलाया जाये (१ करोड़ २० लाख), तो पता चलेगा कि संगठन १९९४-९५ में लगभग १ करोड़ २ लाख नये टीवी सेटों की मांग का अंदाज लगाकर बैठा है। इस बात को यों भी कहा जा सकता है कि १९९४-९५ में देश के एक करोड़ परिवार सिर्फ टीवी सेट खरीदने की ही इच्छा नहीं रखेंगे, बल्कि उनकी आय इतनी बढ़ गयी होगी कि वे १९८८ की कीमत पर टीवी सेट खरीद भी लेंगे। यहां पर यह कहना गलत न होगा कि संगठन ने जो तखमीना प्रस्तुत किया, वह महज उसके आशावादी दृष्टिकोण के और कुछ नहीं है। यदि कहा जाये कि संगठन द्वारा प्रस्तुत किय गया तखमीना परीलोक की कहानी जैसा है, तो भी अतिशयोक्ति न होगी। सवाल उठता कि संगठन के तखमीने को परियों की कहानी बतानेवाले का तर्क क्या है? तो जवाब यह कि मामूली-सी गणित पर यदि ध्यान दिया जाये, तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

खोखलापन: आइये यह मानकर चला जाये कि १९८७ अथवा ८८ में बने कुल १.६ करोड़ टीवी सेट उसी साल बिक गये। चूंकि ज्यादातर एक परिवार एक से ज्यादा टीवी नहीं रखता, इसलिए टीवी धार कुल परिवारों की संख्या भी १.६ करोड़ से कम नहीं हो सकती। १९९० में ऐसे परिवा की संख्या १.९ करोड़ तक जा सकती है।

चूंकि टीवी की कीमत को स्थायी मानकर चला जा रहा है, इसलिए मांग को प्रभावित करनेवाला कारण आय ही हो सक है। अब सवाल यह है कि परिवारों की कुल सख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह २,००० रुपए तथा नगरों में प्रतिम ३,००० रुपए की आमदनी रखता है? क्या यह संख्या आईटीएमए की कल्पना से मेल खाती है?

आईटीएमए का 'मांग अनुमान'

(संख्या लाख में)

वर्ष	ब्लैक एंड ह्वाईट	रंगीन	कुल
१९९०/९१	५५	२०	७५
१९९१/९२	६०	२५	८५
१९९२/९३	६६	३०	९६
१९९३/९४	७३	३५	१०८
१९९४/९५	८०	४०	१२०
पांच वर्षों का योग	३३४	१५०	४८४
जिसमें से:			
निर्यात			४८.४०
पुराने सेटों का-प्रतिस्थापन			५३.२०
नयी मांग			३८२.४०

नोट: (१) निर्यात कुल मांग का १० प्रतिशत माना गया है।
(२) प्रतिस्थापन मांग यह मानकर निकाली गयी है कि टीवी सेट की जिंदगी १० साल होती है।
(३) निर्यात, प्रतिस्थापन, तथा नयी मांगों के आंकड़े, आईटीएमए के नहीं हैं।

एक और अनुमान

१९८८ के मध्य में ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवारों की संख्या १२.४ करो तथा शहरों में ३.६ करोड़ है। ऐसे में टीवी रखनेवाले परिवारों की संख्या १.५ से १. बीच होनी चाहिए। यदि यह मान लिया कि कुल टीवी सेटों का चौथाई भाग ग्रामी क्षेत्रों में है तथा शेष नगरों तथा कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी सेटों की संख्या लग ४० लाख होगी तथा शहरों आदि में १.२ करोड़। यानी ३.२ प्रतिशत ग्रामीण परिवा के पास टीवी सेट हैं तथा शहरी परिवारों कुल संख्या का ३३ प्रतिशत भाग टीवी सेट का मालिक है। यदि १९९४-९५ तक ग्रामी टीवी धारक परिवारों की संख्या १० प्रति होगी, तो टीवी सेटों की संख्या १.४५ करो हो जायेगी। किंतु यदि ग्रामीण टीवी धारक परिवारों की संख्या १५ प्रतिशत होती है, टीवी सेटों की संख्या २.१७ करोड़ हो जायेगी। हालांकि ७ प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के टीवी धारक बनने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसी तरह यदि

ुल शहरी परिवारों का आधा भाग भी टीवी ारक बन जाता है, तो भी टीवी सेटों की ख्या २.२५ करोड़ से अधिक नहीं होगी। तः उपर्युक्त विश्लेषण तथा तथ्यों के आधार र १९९४-९५ तक की स्थिति निम्न हो कती है:

टीवी धारक परिवार १९८८
ग्रामीण: ४० लाख
नगरीय: १.२ करोड़
टीवी धारक परिवार १९९४-९५
ग्रामीण: (क) १.४५ करोड़ (यदि
० प्रतिशत बढ़त हुई)
(ख) २.१७ करोड़ (यदि १५
तिशत बढ़त हुई)
नगरीय: २.२५ करोड़ (५० प्रतिशत
वी धारक होने पर)
कुल (क) ३.७० करोड़
(ख) ४.४२ करोड़

इसलिए आईटीएमए का अनुमान यदि ही होना है, तब तो फिर उपर्युक्त अनुमानों ी और अधिक होना चाहिए। जबकि सच ह है कि ३.५ करोड़ टीवी धारक भी हो ाना गले से उतरता नहीं है।

◆

कपोलकल्पना : आईटीएमए के अनुमान के हिसाब से तो १९९०-९५ के बीच टीवी सेटों की कुल मांग ४.८४ करोड़ होगी (देखें तालिका)। यदि आधा करोड़ निर्यात मान लिया जाये, तो शेष ४.३४ करोड़ घरेलू मांग होगी। इसमें से आधा करोड़ प्रतिस्थापन मांग होगी। यानी १९९०-९५ में ३.८ करोड़ नये परिवार टीवी खरीदेंगे। इस तरह से १९९४-९५ तक टीवी धारक परिवारों की संख्या ६ करोड़ से अधिक हो जायेगी। क्या आईटीएमए का उपर्युक्त अनुमान कपोलकल्पना नहीं है? यह कैसे माना जा सकता है कि इतने कम समय में देश की कुल परिवारों की संख्या का तिहाई भाग टीवी रखने में समर्थ हो जायेगा। यानी इतने परिवारों की आय २००० रुपए प्रतिमाह से ज्यादा होगी। १९८८ में स्थिति यह है कि टीवी धारक परिवार कुल परिवारों के मात्र १० प्रतिशत हैं, उसके बावजूद आलम यह है कि टीवी बिक नहीं रहे हैं और १९९०-९५ के लिए ऐसी कल्पना की जा रही है कि कुल परिवारों की संख्या का तिहाई भाग टीवी खरीदेगा। क्या यह अनुमान अत्यधिक आशावादी नहीं? मौजूदा स्थिति को सामने रखते हुए, तो आईटीएमए के अनुमान में दम नहीं नजर आता।

—कुमारेश चक्रवर्ती

उत्पादन वृद्धि दर ४२ प्रतिशत थी।

मुसीबत की शुरुआत : इसी के बाद शुरुआत हुई, १४ इंच परदेवाले सस्ते ब्लैक एंड ह्वाइट टीवी सेटों को छोड़कर, उत्पादन घटने की। स्थिति यह हो गयी कि ८६-८८ के बीच रंगीन टीवी सेटों की उत्पादन वृद्धि दर मात्र १३ प्रतिशत रही और २० इंच परदे वाले ब्लैक एंड ह्वाइट टीवी की उत्पादन वृद्धि दर, तो मात्र ८ प्रतिशत सालाना रह गयी। इस दौरान १४ इंच वाले टीवी सेटों ने ही टीवी उत्पादन वृद्धि दर को २३.५ प्रतिशत पर बरकरार रखा। (देखें बाक्स) यही वह दौर था, जब प्रसारण केंद्रों की संख्या देश में बढ़ रही थी और ज्यादा-से-ज्यादा आबादी को प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश जारी थी। इसी दौरान कुछ गांवों में विद्युत व्यवस्था भी की गयी थी, ताकि खुशहाल ग्रामीण टीवी सेट खरीदना अपनी जरूरत समझने लगें।

ऐसे में मांग के घटने का कारण समझना कोई मुश्किल बात नहीं। लगता है, देश के जिन हिस्सों में प्रसारण सुविधा उपलब्ध हुई और उन हिस्सों के जितने परिवार टीवी सेट खरीद सकने की स्थिति में थे, उन सब ने टीवी खरीद लिये हैं। अब ये परिवार दुबारा तभी टीवी खरीदेंगे जब उनके पहले के टीवी या तो खराब हो जायेंगे या उनकी हैसियत ब्लैक एंड ह्वाइट की जगह रंगीन टीवी रखने की हो जायेगी। यह भी संभावना है कि इनमें से कुछ के पास यदि बड़े घर होंगे, तो वे जरूरत के हिसाब से एक अदद सेट और खरीद सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में वे १४ इंच वाले सेटों को ही तरजीह देंगे।

वैसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि आगामी वर्षों में १४ इंच वाले ब्लैक एंड ह्वाइट सेटों की ही मांग ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गांवों में २००० रुपए प्रतिमाह तथा नगरों में ३००० रुपए प्रतिमाह वाले आयवर्ग को यही सेट ज्यादा जंचेगा। बाकी रंगीन टीवी सेटों की मांग उन परिवारों के कारण बढ़ सकती है, जिनके पास पहले से ब्लैक एंड-ह्वाइट टीवी मौजूद था और आय बढ़ जाने के कारण वे घर में रंगीन टीवी रखने के इच्छुक होंगे।

भविष्य अच्छा नहीं : जाहिर है, बहुत महंगे रंगीन टीवी सेटों को किसी भी हालत में टीवी की बढ़ती हुई मांग में बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि जिन परिवारों के पास फिलहाल रंगीन टीवी नहीं है, किंतु भविष्य में आय बढ़ने से वे इस लायक हो सकते हैं कि रंगीन टीवी खरीदें, तो भी वे अत्यधिक महंगे टीवी सेटों की ओर नहीं झुकेंगे।

उपर्युक्त विश्लेषण को मद्देनजर रखते हुए यदि आईटीएमए द्वारा दर्शायी गयीं मांग की बढ़त का अध्ययन किया जाये, तो लगेगा कि संगठन ने जरूरत से ज्यादा आशावादी नजरिया अपनाया है। (देखें बाक्स) ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में मांग तेजी से बढ़ने की कोई गुंजाइश यदि बन सकती है, तो एक ही सूरत में कि टीवी के निर्यात को बढ़ावा मिले। किंतु यह सोचना भी गलत है कि निर्यात हमेशा एक-सी छलांग लगाता रहेगा, क्योंकि भारतीय टीवी सेटों की कीमत जापानी तथा ताईवानी टीवी सेटों के मुकाबले लगभग दुगनी होती है। ऐसी हालत में यह कैसे माना जा सकता है कि भारतीय सेटों के निर्यात में बढ़त होती रहेगी।

ऐसी स्थिति में टीवी सेटों की मांग बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह है टीवी सेटों की कीमत में भारी कमी। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि ऐसा करना कंपनियों के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हां, यह जरूर है कि उन्हें ऐसा करने के लिए अपने 'अधिक लाभ' के नजरिये को त्यागना होगा। उल्लेखनीय है कि ६-७ वर्ष पहले मशहूर टेनिस खिलाड़ी (जो एक टीवी कंपनी का मालिक है) ने २० इंच का ब्लैक एंड ह्वाईट टीवी १७०० रुपए का बेचने का साहस किया था। उस समय २० इंच के टीवी सेटों की कीमत सामान्यत: लगभग ३००० रुपए थी। किंतु वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि सरकार तथा उद्योग के दिग्गजों ने उसकी लगाम कस दी थी।

> **यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ एजेंसियां सस्ते दामों पर टीवी बेचना शुरू कर दें, ताकि छोटी कंपनियां 'मौत के आगोश' में न जाने पायें। जाहिर है, जब किस्तों पर टीवी बेचने का दौर चल पड़ा है, तो एजेंसियों द्वारा टीवी बेचने का काम शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं। रही नामी-गिरामी और मजबूत कंपनियों की बात, तो उन्हें जीवित रहने के लिए विज्ञापन युद्ध में बाजी मारनी होगी।**

ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि निकट भविष्य में क्या उपभोक्ता खुद कंपनियों को मजबूर करेंगे कि वे टीवी सेटों के दाम कम करें? १९८९ की स्थिति को देखकर तो लगता है कि जो इस क्षेत्र में जीवित रहना मुश्किल पा रहे हैं, वे इस तरह का जोखिम उठायेंगे, क्योंकि यदि वे ऐसा नही करेंगे, तो उनके समक्ष 'मौत' के सिवा कोई विकल्प नहीं। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ एजेंसियां सस्ते दामों पर टीवी बेचना शुरू कर दें, ताकि छोटी कंपनियां 'मौत के आगोश' में न जाने पायें। जाहिर है, जब किस्तों पर टीवी बेचने का दौर चल पड़ा है, तो एजेंसियों द्वारा टीवी बेचने का काम शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रही नामी-गिरामी और मजबूत कंपनियों की बात, तो उन्हें जीवित रहने के लिए विज्ञापन-युद्ध में बाजी मारनी होगी। ■

शेयर बाजार

उम्मीद की किरण

संसद के वर्षाकालीन सत्र की शुरुआत के समय से शेयर बाजार में आयी मंदी क्या स्थायी है ?

संसद के पावस सत्र की शुरुआत के समय से शेयर बाजार में आयी मंदी के कारण वैसे तो कई हैं, किंतु महत्वपूर्ण कारणों में देश में व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितता का बयान किया जा रहा है। बात सही भी है। संशयपूर्ण राजनीतिक माहौल ने कम-से-कम उन लोगों को तो भयभीत कर ही दिया है, जो शेयर बाजार में सक्रिय थे। नतीजतन लोगों ने राजनीतिक माहौल का जायजा लेकर तरह-तरह की संभावनाएं व्यक्त करनी शुरू कीं। आम धारणा यह बनी कि सरकार शरद ऋतु के अंत में चुनाव करायेगी। यही नहीं, चुनावी नतीजों का भी आकलन शुरू हुआ। कोई मानता है कि राजीव गांधी पुनः बहुमत हासिल करेंगे, तो कुछ मानते हैं कि इस बार उन्हें पहले जैसा बहुमत नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मत है कि राजीव गांधी सत्ता में वापस आयेंगे ही नहीं।

मंदी के कारण: संशयपूर्ण राजनीतिक माहौल तो मंदी का कारण बना ही, उससे भी बढ़कर ज्यादती की यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने। जुलाई के दूसरे पखवारे में यूनिट ट्रस्ट ने शेयर-खरीद पर रोक लगा दी। ऐसे में शेयर बाजार में मंदी स्वाभाविक है। इसके अलावा मंदी का एक और महत्वपूर्ण कारण छोटी आय तथा छोटी पूंजी के लोगों का शेयर बाजार से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग सीधे कंपनी से शेयर खरीदने को तरजीह देते हैं।

शेयर बाजार की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें छोटी पूंजी के लोगों के आकर्षित न होने का एक कारण कंपनियों द्वारा नये शेयर जारी न किया जाना भी है। फिलहाल नामीगिरामी कंपनियां परिवर्तनशील ऋण पत्रों (कनवर्टिबल डिबेंचर्स) का ही धंधा कर रही हैं। यह ऋण पत्र कुछ समय के बाद एक या दो शेयरों में परिवर्तित हो जाते हैं।

नये ऋण पत्रों की बाढ़: खबरों के अनुसार जल्दी ही तरह-तरह के नये ऋण पत्रों से बाजार गर्माने वाला है, क्योंकि नामवर कंपनियों ने बाजार से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने की योजना तैयार की है। जो कंपनियां सितंबर तथा अक्तूबर में नये ऋण पत्र जारी करने जा रही हैं, उनमें सबसे ऊपर लार्सन एंड ट्यूब्रो का नाम है, जो ८०० करोड़ रुपए के परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी करेगी। लार्सन ट्यूब्रो के बाद ओसवाल समूह की बिडला एग्रो का नाम है जो ५०० करोड़ रुपए के परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी करेगी। इनके अलावा एस्सार गुजरात ४०० करोड़ रुपए, एसएम डीहेम २५० करोड़ रुपए, फिनोलेक्स पाइप्स १८० करोड़ रुपए, अपोलो टायर्स १७४ करोड़ रुपए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ९१.७६ करोड़ रुपए, रेमंड वूलेंस ७०.९७ करोड़ रुपए, जेके सिंथेटिक्स ६९ करोड़ रुपए तथा महिंद्रा यूजाईन २० करोड़ रुपए के परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी करेंगी।

कुछ ऋण पत्र जो अगस्त के पहले पखवारे में उपलब्ध होगें उनको तरजीह दी जा सकती है। इसमें अरविंद मिल के ऋण पत्र भी हैं। जाहिर है, अरविंद मिल अपनी डेनिम के लिए तो मशहूर है ही, साथ में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, दवाओं तथा टीवी उद्योग आदि में भी उसकी अच्छी पैठ है तथा उसके उत्पादों ने काफी नाम कमाया है। अरविंद मिल १२० रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से ४ लाख ३३ हजार ऋण पत्र जारी करेगी जिस पर १२.५ प्रतिशत ब्याज देय होगा।

फायदेमंद शेयर: इसी तरह अनंत राज क्ले प्रोडक्ट्स १९८५ में पंजीकृत नयी कंपनी है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद सिरेमिक टाइल रहा है। इस कंपनी ने लंदन की हेंशाल बेमफोर्ड कंपनी से हाथ मिला लिया है तथा अपने उत्पाद के लिए इटली की 'मोनी स्पा' कंपनी से मशीनें आदि खरीद ली हैं। यही नहीं, इस कंपनी के उत्पाद की देश-विदेश में काफी मांग है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस कंपनी का भविष्य काफी अच्छा है। यह कंपनी बि किसी प्रीमियम के १३.९४ लाख शेयर १० प्रति शेयर के हिसाब से बेचेगी। छोटी पूंजी के लो के लिए ये शेयर काफी आकर्षक होंगे। यह सही कि पलक झपकते ही बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं जा सकती, किंतु यह कहा जा सकता है कि कंपनी के शेयर खरीदने में नुकसान नहीं होगा। य नहीं, इन शेयरों को भी आयकर तथा संपत्ति की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कम-से-कम अ पांच साल तक ७,००० रुपए तक का लाभांश मुक्त' होगा। ये शेयर १० अगस्त को जारी हों

अगस्त माह से डीसीएल पोलिएस्टर कंप पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न का उत्पादन शुरू देगी। इससे पूर्व कंपनी ने सर्वेक्षण कराके अ उत्पाद की मांग का आकलन कर लिया है। सर्वे के अनुसार ८९-९० में यह मांग एक साल १४८,६०० टन होगी, जो १९९४-९५ ३६९,७८० टन हो जायेगी। स्थिति यह है कि में फिलहाल लाइसेंसधारी कंपनियां मात्र ८२१ टन यार्न के उत्पादन की क्षमता रखती हैं। ऐसे में कहना गलत न होगा कि डीसीएल का भवि अच्छा है। यह कंपनी १० रुपए प्रति शेयर के हिस से ७९ लाख शेयर बेचेगी। जाहिर है, ये शेयर छोटी पूंजी के लोगों के लिए फायदेमंद होंगे।

एग्रो केमिकल्स का चमत्कार: इसी त वेरिंदर एग्रो केमिकल्स भी चमत्कार करने के लि मशहूर है। चार साल में ही यह कंपनी टैक्स अ अदा करने के बाद ३.३४ करोड़ रुपए लाभ कमा सफल हुई। यही नहीं, इस कंपनी ने पंजाब के सु फास्फेट के कुल बाजार में से आधे पर कब्जा रखा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब भारत का अके सबसे बड़ा सुपर फास्फेट का उपभोक्ता है। कंपनी के विशेषज्ञों का अनुमान है कि उसकी बि अगले साल ३० करोड़ रुपए तक जायेगी और ला ५ करोड़ रुपए तक होगा। जनता से १.६९ करो रुपए उगाहने के लिए इस कंपनी ने २२५ रुपए प्र ऋण पत्र के हिसाब से पूर्ण परिवर्तनशील ऋण जारी करने की योजना बनायी है। कई ऋण हासिल करना बड़ी मुश्किल बात होगी, क्यों अभी से यह अनुमान है कि अपेक्षाकृत अधिक लो ऋण पत्र लेने के उत्सुक होंगे। किंतु इस ऋण पत्र संबंध में यह जरूर कहा जा सकता है कि जो जि ज्यादा ऋण पत्र हासिल कर लेगा, वह उतना ज्यादा फायदेमंद होगा।

—नंदिनी चक्रव

> खबरों के अनुसार जल्दी ही तरह-तरह के नये ऋण पत्रों से बाजार गर्माने वाला है, क्योंकि नामवर कंपनियों ने बाजार से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने की योजना तैयार की है। जो कंपनियां सितंबर तथा अक्टूबर में नये ऋण पत्र जारी करने जा रही हैं, उनमें सबसे ऊपर लार्सन एंड ट्यूब्रो का नाम है, जो ८०० करोड़ रुपए के परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी करेगी।

श्रीमती ताराअली बेग

अनुकरणीय, किंतु उपेक्षित

संसद में गहमागहमी, श्रीलंका के साथ नोक-झोंक तथा सड़क दुर्घटनाओं की सुर्खियों के कारण तारा अली बेग के निधन को वैसी प्रमुखता नहीं मिल पायी, जैसी कि मिलनी चाहिए थी। सच तो यह हैं कि संवेदनशीलता का दम भरनेवाले बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों तक में तारा अली बेग के निधन को लेकर वांछित प्रतिक्रिया नहीं हुई।

यह संयोग ही है कि तारा अली बेग के निधन के कुछ ही समय पूर्व इस संवाददाता ने उनकी एक लंबी भेंटवार्ता रिकार्ड की थी, जिसमें महिला उत्थान एवं बाल कल्याण पर उनके विस्तृत विचार, भावी योजनाएं और अब तक की उपलब्धियों का लेखाजोखा था। अपने आप में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग अपना पूरा जीवन, समाज में महिलाओं को उनका समुचित स्थान दिलाने और बच्चों को सही मायने में देश का कर्णधार बनाने के लिए अर्पित कर देने के बावजूद तारा अली बेग की पहचान नयी पीढ़ी की नहीं के बराबर है।

मसूरी में जन्म लेने के बाद तारा अली बेग ने क्रमशः दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड और ढाका में शिक्षा ग्रहण की। तारा अली की मां अमरीकी और पिता भारतीय थे। तारा अली बेग ने जीवनपर्यंत पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के उत्कृष्ट संगम का अनुकरणीय दृष्टांत तो उपस्थित किया ही, किसी भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अपने-आप को दूर भी रखा। वह भी तब जबकि भारत आने के साथ ही उनका निकट संपर्क राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सरीक़े राजनेताओं से जुड़ गया था और उनके पति मिर्जा राशिद अली बेग भारतीय विदेश सेवा के एक उच्च अधिकारी थे।

तारा अली बेग का योगदान इसलिए भी स्मरणीय है कि उन्होंने न केवल विविध क्षेत्रों में पहल की, बल्कि भविष्य के लिए सुनियोजित ढांचा भी तैयार किया। अपने आत्म-कथात्मक संस्मरण 'पोर्ट्रेट्स आफ एन एरा' में तारा अली बेग ने अपने जीवन के सभी दायरों की चर्चा की है।

तारा अली बेग का बचपन राजमाता देवपुर, सेनापति थिमैया एवं चौधरी तथा प्रख्यात अभिनेत्री देविका रानी जैसों के साथ बीता। कालांतर में उनका निकट परिचय ख्रुश्चेव, बुलगानिन, आइजनहावर, महारानी एलिजाबेथ, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, माउंटबेटन दंपती सरीखे लोगों से हुआ जिन्होंने स्वाधीन भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की थीं। तारा अली बेग की दूरदर्शिता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से तीस वर्ष पूर्व ही महिलाओं के उत्थान की योजना बनायी थी, जबकि आज भी महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने बच्चों में साहसिक प्रवृत्ति को विकसित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा ठोस कार्यक्रम तैयार किया जो आज के संदर्भों में भी सर्वोत्तम है। संजय और गीता चोपड़ा के नाम से साहसी बच्चों को पुरस्कृत करना इनके दिमाग की ही उपज थी।

१९३७ में स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने तारा अली बेग को महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों का अध्ययन करने वाले ग्रुप का संयोजक नियुक्त किया जो प्रथम योजना समिति का हिस्सा था। हालांकि उनके पति स्वाधीनता से पूर्व ही विदेश सेवा में नियुक्त थे, परंतु इससे उनकी समाज-सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तविकता तो यह थी

(साक्षात्कार/तारा अली बेग)

महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गयी हैं

माया: *आपने महिला उत्थान एवं बाल कल्याण के लिए एक समर्पित जीवन जिया है, क्या तीन दशकों के बाद आपको कोई आधारभूत अंतर नजर आता है?*

बेग: हां, आज महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात महज शास्त्रीय बहस बनकर नहीं रह गयी है। अनेक क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधे मिलाकर चल ही नहीं रहीं, बल्कि उनसे आगे भी निकल गयी हैं। सेना में जनरल के ओहदे पर, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य आदि सभी पर तो महिलाएं रह चुकी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये स्थितियां महज अपवादस्वरूप नहीं थीं।

माया: *बाल कल्याण के क्षेत्र में आज के संदर्भ में आपका क्या मत है?*

बेग: बच्चों के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सिर्फ चंद राज्यों में निःशुल्क मध्याह्न चना-चबैना सुलभ करा देने या नयी शिक्षा नीति के नाम पर बच्चों को भारी-भरकम स्कूली बस्ते लादने पर विवश कर देने से कुछ नहीं हासिल होनेवाला। वयस्कों की तुलना में बच्चे कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा।

माया: *बाल कल्याण की जिम्मेदारी केंद्रीय काबीने में अलग से एक मंत्री को सौंप देने से क्या कुछ विशेष हो सकने की संभावना है?*

बेग: (हंसी और खामोशी)

माया: *महिलाओं और उनकी समस्याओं से जुड़े कुछ विशेष सीरियल दूरदर्शन पर दिखलाये गये थे। मसलन-अधिकार, तेरह पन्ने, रजनी आदि। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे कहां तक सफल रहे?*

बेग: अव्वल तो महिलाओं के लिए अलग से सीरियल बनाने की बात सिद्धांत रूप में ही गलत है। ऐसा करने से महिलाओं की बेचारगी और उजागर होती है और पुरुषों पर उनकी निर्भरता भी। वास्तव में पुरुष की अपेक्षा नारी अधिक सहिष्णु और समर्थ है और कमोबेश स्वयं ही वह अपनी समस्याओं से जूझती रहती है। दूरदर्शन सीरियल कल्पना के स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को लेते और उनका समाधान सुझाते रहे, जिनका वास्तविकता से दूर का भी कोई संबंध नहीं था।

माया: *राजनीतिक जीवन को आपने तरजीह क्यों नहीं दी?*

बेग: इसके प्रति न मेरा झुकाव था और न ही समय। लोगों को भ्रम है कि राजनेता ही रामबाण औषधि दे सकता है। यह गलत है। ठोस रचनात्मक कार्य के लिए और मंच भी हैं।

माया: *भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?*

बेग: भविष्य तो अभी बहुत दूर का क्षितिज लगता है। अभी तो मुझे वर्तमान में ही जीना है। वर्तमान के दायित्वों को पूरा कर लेने के बाद ही कुछ कह सकूंगी। —शी०प०

'क्यू' मार्क योजना अपनाने के लिये उद्यमियों का आवाहन

१. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादन के गुण स्तर में सुधार लाने एवं उपभोक्ताओं को अच्छे गुण स्तर का माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वस्तुओं को 'क्यू' मार्क प्रदान किया जाता है।

२. हस्तकला वस्तुओं को भी विभागीय मानकों के आधार पर 'क्यू' मार्क प्रदान किया जाता है।

३. 'क्यू' मार्क प्रदान करने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण एवं परीक्षण योग्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

४. आई०एस०आई० मार्क वस्तुओं की ही भांति 'क्यू' मार्क वस्तुएं भी गुण वत्ता का प्रतीक हैं।

५. 'क्यू' मार्क वस्तुएं भरोसेमन्द, मजबूत एवं टिकाऊ होती है क्योंकि इन वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने के बाद ही 'क्यू' मार्क प्रदान किया जाता है।

६. 'क्यू' मार्क वस्तुओं को निर्यात एवं शासकीय भण्डार क्रय में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

उत्पादकों को अपने व्यापार में समृद्धि लाने एवं उपभोक्ताओं को अच्छे गुण स्तर का माल उपलब्ध कराने तथा गुण वत्ता हेतु उपभोक्ताओं में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु इस योजना का सदस्य बनने के लिये सादर आमंत्रित किया जाता हैं विशेष जानकारी हेतु उद्योग निदेशालय, उ०प्र० जी०टी रोड़, कानपुर अथवा अपने जिले के महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करें।

(देवी दयाल)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०

तारा अली बेग के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी शायद यह थी कि वे अपने कार्य और अपनी बात के लिए सभी उपलब्ध मंचों का बेहतर इस्तेमाल करती थीं। समाचारपत्र-पत्रिकाओं में तो वे नियमित लिखती ही थीं, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात करोड़ों श्रोताओं तथा दर्शकों तक पहुंचायी।

कि अपने पति के साथ विदेश में रहते हुए भी उन्हों प्रतिबद्धता के नये क्षितिज खोज निकाले।

इंडोनेशिया में उन्होंने महिलाओं क अंतरराष्ट्रीय क्लब स्थापित किया। जब वे ईरा गयीं, तो वहां भी उन्होंने वैसा ही एक अन्य क्ल स्थापित किया। भारत लौटने के तुरंत बाद ता अली बेग जी-जान से बाल कल्याण परिषद संस्थापन के काम में लग गयीं। आगामी वर्षों इंदिरा गांधी तक इसकी अध्यक्ष रहीं। इंदिरा गां के राजनीतिक दायित्वों के बढ़ने के साथ परिषद बागडोर स्वतः तारा अली बेग के हाथ में आ गयी अनेक वर्षों तक पत्नी, मां और समाजसेविका तिहरी भूमिका वे बखूबी निभाती रहीं। बा कल्याण के लिए उन्होंने भारत में भी अपन गतिविधियों को शुरू करने के लिए यूनीसेफ तक राजी किया।

१९७७ में बाल कल्याण के निमित्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असाधारण योगदान के लि तारा अली बेग को जेनेवा में (पांच वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल कल्याण संघ का अध्यक्ष चु गया। इस पद पर रहने वाली वे प्रथम एशिया महिला थीं। तिब्बती गृह संस्थान और एसओए बालग्रामों की भारतीय शाखा की अध्यक्ष भी रहीं। यह तारा अली बेग की बहुमुखी प्रतिभा का कमाल था कि वे शहरी, ग्रामीण एवं जनजाती महिलाओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए 'श्रुति' जै संस्था स्थापित कर सकीं।

सम्मान: अपने अद्भुत योगदान के लि उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रा हुए। इनमें १९६५ में तेहरान के समाज-का विद्यालय का विशिष्ट सम्मान एवं मानद उपाधि एसओएस के अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा वर्ष १९७ में सोने की पिन, १९८४ में अंतरराष्ट्रीय बा कल्याण संघ का विशेष पुरस्कार और १९८४ में ही बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं तारा अली बेग के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खू शायद यह थी कि वे अपने कार्य और अपनी बात लिए सभी उपलब्ध मंचों का बेहतर इस्तेमाल कर थीं। समाचारपत्र-पत्रिकाओं में तो वे नियमि लिखती ही थीं, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम भी उन्होंने अपनी बात करोड़ों श्रोताओं तथा दर्श तक पहुंचायी। अविक घोष के साथ मिलकर ता अली बेग ने 'गेट वे टु इंडिया' नामक एक रोच सीरियल का निर्माण भी किया। अपने संस्मरणों अलावा उन्होंने चार पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें से बच्चों के लिए हैं। इतनी उपलब्धियों के बावजू पता नहीं क्यों उन्हें सरकारी उपाधियों से वंचि रखा गया। हालांकि, ऐसी विभूति को अलंकृत कर पर उपाधि का ही मान बढ़ता। वैसे, उसकी दरका तारा अली बेग को थी भी नहीं, क्योंकि बा कल्याण परिषद अपने आप में एक जीता-जागत स्मारक है, जो आने वाली पीढ़ियों को तारा अली बेग की याद दिलाता रहेगा।

—शीला

जापान

राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू

जुलाई के आरंभ में तोक्यो नगरसभा के चुनावों में मुंह की खाने के बाद जापान की शासक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जापानी संसद के ऊपरी सदन में भी जबर्दस्त हार का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री सोसुके उनो ने इस हार के लिए स्वयं को उत्तरदायी बताते हुए ५३ दिनों के कार्यकाल के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री नें इतने अल्पकाल में ही कुरसी त्याग दी। उनो से पूर्व प्रधानमंत्री तंजान इशीबाशी की मिसाल है, जिनका कार्यकाल (२३ दिसंबर १९५६ से २५ फरवरी १९५७) दो माह था। उनो ने इस्तीफा देते समय कहा, "रिक्रूट भ्रष्टाचार, तीन प्रतिशत की दर से बिक्रीकर लगाये जाने तथा सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की आयात नीति उदार बना दिये जाने से जापानी जनता के विभिन्न वर्ग शासक दल से नाराज हो गये और उन्होंने मौका मिलते ही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक दे दिया।"

हार के लिए जिम्मेदार : मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री सोसुके उनो ने इस हार के लिए अपने प्रेम प्रसंगों को जिम्मेदार नहीं बताया। पर सचाई यह है कि गीशा मित्सुको नकानिशी के साथ उनके यौनाचार की जो कहानियां छपीं और नकानिशी ने स्वयं दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री को जिस तरह हृदयहीन बताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के पद के अयोग्य बताया, उसका मतदाता पर काफी असर पड़ा। नतीजतन जापान की महिलाएं, शासक दल के विरुद्ध हो गयीं जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री को चुनाव में भुगतना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि रिक्रूट कांड का भेद खुलने और प्रधानमंत्री ताकेशिता के इस्तीफे के बाद सोसुके उनो ३ जून को जापान के प्रधानमंत्री बने थे। तब वे पार्टी के सबसे पाक-साफ व्यक्ति नजर आये थे। पर एक महीने के अंदर ही उनके पट खुलने लगे और वे जापान के चरित्रहीन प्रधानमंत्री के रूप में उभरे। यह विवाद इतना तूल पकड़ गया कि उनो पर दबाव पड़ने लगा कि वे इस्तीफा दे दें। शुरू में तो उनो ने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया और कहा कि निजी मामलों को राजनीतिक निर्णयों का आधार नहीं बनाया जा सकता। पर शोर बढ़ने पर उन्होंने ये संकेत दिये थे कि अपने और पार्टी के हित में इस्तीफा देना ही बेहतर होगा।

नगरसभा के चुनाव: हुआ यह कि प्रधानमंत्री उनो दुविधा की स्थिति में झूल रहे थे कि तोक्यो नगरसभा के चुनाव सिर पर आ गये। इसके लगभग तीन सप्ताह बाद जापानी संसद के ऊपरी सदन की आधी सीटों का चुनाव होना था। ऐसे मौके पर, पार्टी के व्यापक हित में यही उचित समझा गया कि प्रधानमंत्री उनो अपने पद पर बने रहें।

२ जुलाई को पालिका चुनाव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ा निराशाजनक रहा। पिछली पालिका सभा की १२८ सीटों में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ६३ सदस्य थे। ताजा पालिका चुनावों के बाद उनकी संख्या में २० की कमी आयी और अब पालिका सभा में इस पार्टी के ४३ सदस्य ही रह गये हैं। जबकि लिबरल पार्टी की हार का लाभ जापान की सोशलिस्ट पार्टी को मिला और पचास के दशक से लेकर अब तक पहला मौका था, जब समाजवादियों ने पालिका सभा की ३६ सीटें जीतीं।

विपक्ष का वार : खबरों के अनुसार पालिका सभा के चुनाव प्रचार के दौरान जापानी समाजवादी पार्टी ने अपनी मौलिक नीतियों पर चर्चा करने के बजाय लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पर सीधा प्रहार किया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की 'कर' नीतियों, रिक्रूट भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री उनो के यौनाचार की भी चर्चा की गयी। इस मौके पर गीशा नकानिशी ने कहा कि जो पुरुष अबला के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह देश का प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है। यही नहीं, जापानी सोशलिस्ट पार्टी ने समाजवादी सांसद मनाये कुबोता के संसद में दिये गये भाषण के एक वाक्य को भी खूब प्रचारित किया, जिसमें मनाये कुबोता ने कहा था, "प्रधानमंत्री उनो तो स्त्रियों को तरकारी-भाजी समझते हैं।" नतीजतन जनता, खासतौर से महिलाएं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज हो गयीं। जापानी समाजवादी पार्टी को तो जो बड़ा लाभ मिला सो मिला ही, जापान की अन्य प्रतिपक्षी पार्टियां भी लाभ से वंचित नहीं रहीं। पालिका सभा में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति तीन से बढ़कर पांच हो गयी लेकिन बौद्धों की 'कोमेई' पार्टी ने तीन सीटें गवां दीं और जापानी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति २० से घटकर १४ हो गयी। पालिका सभा चुनाव में पराजय का मुंह देखने के बाद चीन में लोकतंत्र की मांग को जिस तरह दबाया गया, उसको एक नमूने के रूप में पेश करते हुए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि जापानी समझ सकते हैं कि यदि जापान में भी कम्युनिस्टों ने अपने पैर जमाये तब क्या होगा।

सोसुके उनो

पहले वे पार्टी के सबसे स्वच्छ व्यक्ति नजर आये, पर एक महीने के अंदर ही उनके पट खुलने लगे और वे एक चरित्रहीन प्रधानमंत्री के रूप में उभरे।

पराजय संसद में भी: बहरहाल तोक्यो पालिका सभा के चुनाव परिणाम संसद के ऊपरी सदन के चुनाव की परखनली साबित हुए। २३ जुलाई को हुए चुनाव में संसद के ऊपरी सदन की २५२ सीटों में से आधी दांव पर लगी थीं। उल्लेखनीय है कि सदन में १९५५ से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बराबर बहुमत में रही, पर इस बार चुनाव में करीब ३० सीटें पार्टी के हाथ से निकल गयीं। सदन में उसकी शक्ति घटकर अब १०९ रह गयी है। प्रतिपक्ष की कुल शक्ति बढ़कर १४३ पर पहुंच गयी है। सबसे अधिक लाभ जापान की समाजवादी पार्टी को हुआ है। चुनाव से पूर्व ऊपरी सदन में उसे ४३ स्थान प्राप्त थे, जो अब बढ़कर ६७ हो गये हैं। मजदूर यूनियनों के नये महासंघ 'रेंगो' ने १२ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये और ११ सीटें जीतीं। यह पार्टी भी समाजवादी पार्टी की समर्थक है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का जापानी संसद की लोकसभा में बहुमत तो है, पर राज्यसभा में शासक दल के अल्पमत में पहुंच जाने के बाद देश में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। बात सही भी है। ऊपरी सदन निचले सदन से आनेवाले विधेयकों को अस्वीकार कर सकता है। बजट पास करने में भी ३० दिन का विलंब किया जा सकता है। वैसे संविधान की व्यवस्था के अनुसार ऊपरी सदन से लौटाये जानेवाले विधेयकों को लोकसभा फिर पारित कर सकती है, पर ऐसी स्थिति में उसे विधेयक के पक्ष में दो तिहाई बहुमत की व्यवस्था करनी होगी। यही नहीं, संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री को दोनों सदनों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा ऊपरी सदन में बहुमत न रहने पर प्रतिपक्ष संयुक्त रूप से सरकार का चलना दूभर कर सकता है। लोकसभा में विपक्ष की कुल शक्ति सदन की एक तिहाई से अधिक हो गयी है। ऐसी स्थिति में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के लिए यह संभव न होगा कि ऊपरी सदन से लौटनेवाले विधेयकों को फिर पारित करा सके।

डांवाडोल भविष्य: बहरहाल समाजवादी तो यही चाहेंगे कि सरकार को लकवे की स्थिति में डालकर उसका चलना-फिरना मुश्किल कर दें, ताकि आम चुनाव अनिवार्य हो जायें। पर चुनावों से सरकार की लकवे की स्थिति का अंत हो पायेगा, यह कहना मुश्किल है। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि विपक्षी दल एकजुट रहते हैं या नहीं, क्योंकि शासक दल तो पूरा जोर लगायेगा कि प्रतिपक्ष एक न रहने पाये।

—रामपाल सिंह

जीतेगा भई जीतेगा, पहलवान जीतेगा

ममता कालिया

राज्य के दो प्रमुख नगरों में नगरपालिका चुनाव की घोषणा क्या हुई कि जैसे तूफान आ गया। शोर, धूल, गंदगी, गुंडागर्दी, भाषणबाजी, गाना बजाना, नारेबाजी, अड्डेबाजी, सबकी बन आयी। सभासद पद के प्रत्याशी सफेद बुर्राक पोशाक में, अपने समर्थकों के साथ घर-घर हिनहिना रहे हैं, 'आपका अपना साथी हूं,वोट जरूर दीजिए।' घरों के बाहर पड़ा कूड़ा उन्हें विचलित नहीं करता। मुहल्लों के सूखे नल, टोंटियां, उखड़े हैंडपंप सब मानो। चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं, 'ए उम्मीदवार, पहले हमारी तरफ देखो, तब वाट मांगो।' प्रत्याशी कहते हैं 'गलत, पहले वोट, बाद में मरम्मत।' चुनाव-प्रचार में हाथी, घोड़े, ऊंट, टैंपो, ट्रैक्टर, स्कूटर और लता मंगेशकर का इस्तेमाल हो रहा है। रेकार्ड प्लेयर नया हो या पुराना, लाउडस्पीकर साबुत हो या फटा, लता मंगेशकर का स्वर इन सब को चीरता हुआ दिग-दिगंत में गूंज रहा है।

अप्रतिम प्रतिभा की धनी इस राष्ट्रीय कलाकार का एक अन्य भयावह उपयोग किया जाता है आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा। जब भी कभी किसी राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय नेता का निधन होता है, सुबह से शाम तक लता मंगेशकर राष्ट्र के आंख-कान में राष्ट्रीय शोक-गान करती दिखाई-सुनाई पड़ती हैं। कभी उनके गाये, भजन और दोहे परदे पर आते हैं, कभी गीता के श्लोक। उस दिन मानो पूरा स्टाफ छुट्टी मनाता है—अगले तीन दिन लता मंगेशकर की ड्यूटी है, दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि, उसकी आत्मा के लिए शांति-पाठ, संसार की असारता और ईश्वर की महिमा का बखान सब लता मंगेशकर के जिम्मे है। बीच-बीच में कुछ अन्य महान राष्ट्रीय कलाकारों की आवाज मुख्य कलाकार को रिलीफ दे देती हैं—एमएस सुब्बलक्ष्मी, आशा भोंसले, गिरजा देवी। लेकिन असली भार लता मंगेशकर के कंधों पर रहता है। रेडियो और दूरदर्शन के हजारों अधिकारी और कलाकार मिलकर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दे पाते जिसमें दिवंगत के प्रति सम्मान के साथ-साथ अवसर का गाम्भीर्य, अवसाद और दर्शन प्रतिबिंबित हो सके।

मैं नहीं जानती लता मंगेशकर को अपनी कला का यह इस्तेमाल कैसा लगता होगा। ख्याति के जिस शिखर पर वे पहुंच चुकी हैं, उनके लिए यह कोई उत्साहवर्धक बात नहीं होगी कि हर गली-चौराहे पर हर सुर-बेसुरे अवसर पर उन्हें अपनी आवाज का सामना करना पड़े, न ही उनके हृदय में आकाशवाणी-दूरदर्शन से कवरेज पाने की ललक होगी। निश्चित ही उनके अंतर का कलाकार हताश होता होगा। हैरानी इस बात की है कि उनकी आवाज, इस तमाम व्यवसायीकरण के बावजूद जीवित है अपनी पूरी स्वच्छता, तेजस्विता और मधुरता के साथ।

यह ठीक है कि कला को प्रायः मनोरंजन का साधन समझा जाता है। मनोरंजन करना कला का गुण हो सकता है, लक्ष्य नहीं। विभिन्न कलाएं मानव सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करती हैं, जीवन को परिष्कृत बनाती हैं, आनंद प्रेरणा देती हैं, नवजीवन का संदेश देती हैं। कला के संपर्क हमारे अंतर के संवेश जागते हैं। संगीत यह कार्य सबसे और सुंदर तरीके से करता है। लेकिन चुनाव के दिनों में संगीत प्राणदंड जैसा जान पड़ता है।

नगर की धजा और सभासद पद के उम्मीदवारों धमाचौकड़ी देखकर जनता समझ गयी है कि आनेवाले दिनों आम चुनाव का चेहरा कैसा होगा। इसी तरह जीपें दौड़ें लाउडस्पीकर भौंकेंगे, पोस्टर दीवारें गंदी करेंगे, नंबर दो ताकत सींग लड़ायेगी, अपराधी आतंक फैलायेंगे, बाजार कीमतें बढ़ेंगी, मतदान के दिन फर्जी वोट पड़ेंगे और मिलाकर लोकतंत्र का यह पावन मंत्र 'चुनाव' चिथड़े- किया जायेगा। यह चुनाव महज एक रिहर्सल है उस बड़े चुनाव का जिसमें यह सारा शक्ति-प्रदर्शन राष्ट्रीय पैमाने होगा।

यह देखना भी जरूरी है कि जब चुनाव में जनता दिलचस्पी इतनी कम है, तब आखिर वे कौन लोग हैं जो लड़ते हैं। इसकी पहचान कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एक क्षेत्र में दो ऐसे लोग हैं जो पेशे, स्वभाव और सरोकार एकदम अलग हैं—एक अपने खाली वक्त में लोगों के दुख- सुनता है, उनकी सहायता करता है, लोगों की खातिर से भी भिड़ जाता है, दूसरा ज्यादातर अपने ठिकाने से दूर है, वक्त बेवक्त घर आता-जाता है, अफवाहों के केंद्र में जिक्र होता है, उसके सामने पड़ने से हर शरीफ आदमी हैं, पुलिस जिसकी बगलगीर रहती है और अपराधी अंगरक्षक, तो यह तय है कि चुनाव के लिए टिकट इस प्रत्याशी को मिलेगा। पहले का नाम एकदम पहले चर्चा में आयेगा लेकिन कार्यकारिणी की फाइनल बैठक में कहकर रद्द कर दिया जायेगा कि यह पहला जरूरत से 'सीधा' है, हार जायेगा। वह दूसरा डैशिंग है, हारना उसे ही नहीं, वह हर हालत में जीतेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी न करना पड़े। यह विपक्ष को पटकनी लगायेगा, यह इलाके सारे तत्वों पर राज करेगा। यह समर्थ आदमी है, जरूरत पर भीड़ लायेगा, पैसा लायेगा और लाठी से लेकर बम चलायेगा। यह अपनी मौलिकता से परेशान नहीं सज्जनता को सिरदर्द नहीं बनायेगा, सचाई का सलीब उठायेगा और आम जनता को इसकी हद में रखेगा। इसके में शराब के ठेके हैं, अपराध के लाल-हरे इलाके हैं, ऐय्याशी अड्डे हैं। कहने का मतलब यह कि जिन सब कारणों के शरीफ आदमियों के बीच उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध उन्हीं सब कारणों के रहते चुनाव में उसकी विश्वसनीय कायम होगी। यह एक भयावह सच है कि आज का इतना हताश है कि वह लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया चुनाव नितांत उदासीन हो गया है। इसीलिए जब जनसंपर्क के चुनाव के प्रत्याशी, आदर्शवादी युनिफार्म में सजे, जीप में जोड़ कर सड़क पर निकलते हैं और उनके समर्थक गला चिल्लाते हैं 'जीतेगा भई जीतेगा, पहलवान जीतेगा' तब आदमी सबसे पहले घर की खिड़की बंद कर लेता है और दरवाजा।

> **यह एक भयावह सच है कि आज का आदमी इतना हताश है कि वह लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया चुनाव से नितांत उदासीन हो गया है। इसीलिए जब जनसंपर्क के लिए, चुनाव के प्रत्याशी, आदर्शवादी युनिफार्म में सजे, जीप में हाथ जोड़ कर सड़क पर निकलते हैं और उनके समर्थक गला फाड़ चिल्लाते हैं 'जीतेगा भई जीतेगा, पहलवान जीतेगा' तब आम आदमी सबसे पहले घर की खिड़की बंद कर लेता है और फिर दरवाजा।**

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ से.मि. एफ.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे का टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली ख़ूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?

ओनिडा २१
पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

क्या नए
ओनिडा पर प्रतिबंध
लगाया जाए?

सुरीला हिंदुस्तान

लोक संगीत की तलाश

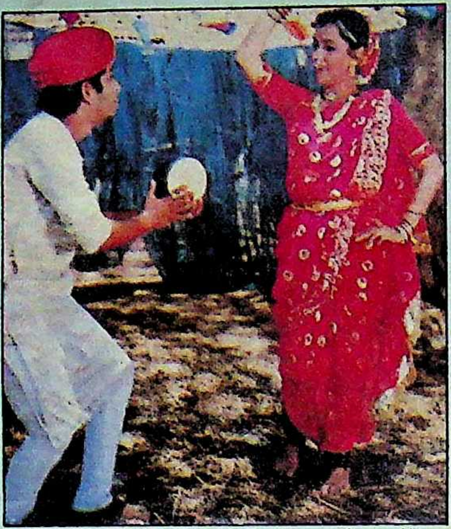

महाराष्ट्र के लावनी लोकनृत्य में वंदना राणे (दायें)

"जिस दौर में हिंदी फिल्म संगीत अपने स्वर्णिम काल में था, उसका प्रमुख आधार था—लोक संगीत। बाद में यह आधार खिसक गया और फिल्म संगीत पाश्चात्य धुनों की अंधी नकल तथा शोर-शराबे से भरा संगीत होकर रह गया। फलतः फिल्मी गीतों की उम्र सालों तक लंबी होने के बजाय हफ्तों, फिर मात्र हफ्ते तक रह गयी। नतीजतन देश का विशाल संगीत-प्रेमी जनसमुदाय फिल्म संगीत से निराश होकर गैर-फिल्मी गायन में सुकून ढूंढ़ने लगा। इसी बात ने मुझे 'सुरीला हिंदुस्तान' बनाने की प्रेरणा दी।" कहनेवाले प्रख्यात कथाकार-पत्रकार एवं संगीत-समीक्षक हरीश तिवारी का टीवी सीरियल 'सुरीला हिंदुस्तान' देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोक संगीत और लोक नृत्य को उनके मूल रूप में उजागर करता है।

"यह तो सिर्फ लोक संगीत की तलाश की यात्रा का प्रारंभ मात्र है।" हरीश तिवारी बतलाते हैं, "हमारे विशाल देश में लोक संगीत का इतना समृद्ध खजाना है कि उसकी तह-दर-तह में पहुंचने में ही वर्षों लग जायेंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी इस समृद्ध परंपरा से बड़ी तेजी से कटती जा रही है। अगर हमने अभी इस प्रवृत्ति पर ब्रेक नहीं लगाया, तो हमारा इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। लोक संगीत को आम आदमी से परिचित कराने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम दूरदर्शन है, इसीलिए मैंने उनके आफर को तुरंत स्वीकार कर लिया और पूरी कोशिश की कि सार-संक्षेप में उन्हें इस धरोहर से सहज साक्षात्कार करा सकूं।"

कुछ वर्ष पहले एक दिन हरीश तिवारी एक मित्र के घर गये हुए थे। इत्तफाक से उसी रात दूरदर्शन पर एक बहुत पुरानी संगीत प्रधान फिल्म 'अनमोल घड़ी' टेलीकास्ट हुई। घर की किशोर और युवा पीढ़ी ने फिल्म देखने के बजाय अपने कमरे में माइकल जैकसन का कैसेट सुनना और उस पर नृत्य करना ज्यादा पसंद किया। "इस बात ने मुझे बेतरह झकझोरा।" हरीश तिवारी बतलाते हैं, "मुझे सबसे ज्यादा झटका तो तब लगा, जब यह पता चला कि लड़के-लड़कियां, हिंदी कवियों तथा उर्दू शायरों के नाम तक नहीं जानते।"

इस झटके ने हरीश तिवारी को 'अमृता' सीरियल बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने हिंदी-उर्दू के महान कवियों-शायरों की चुनिंदा रचनाओं को दृश्य (विजुअल) माध्यम से दूरदर्शन पर पेश करने की योजना बनायी। इस योजना में सहयोग देने के लिए (स्व०) पं० नरेंद्र शर्मा भी आगे आ गये। संगीतकार स्व० जयदेव ने एक-एक गीत को बड़ी मेहनत से धुनों में बांधा, लेकिन 'अमृता' के निर्माता-निर्देशक ने इसे कविता और शायरी का सतही छायागीत बना डाला। फलतः 'अमृता' हिंदी-उर्दू के शीर्षस्थ कवियों-शायरों की खिल्ली उड़ानेवाला सीरियल भर बन कर रह गया। इस साहित्य-दुर्दशा के कारण हरीश तिवारी ने 'अमृता' के चार एपीसोडों के बाद उससे किनारा कस लिया, लेकिन लोक संगीत तथा साहित्य के प्रति अगाध निष्ठा उन्हें हर क्षण बेचैन किये रही।

लोकसंगीत का मानचित्र: "मैं 'सुरीला हिंदुस्तान' को सिर्फ लोक संगीत का मानचित्र भर मानता हूं।" हरीश तिवारी बतलाते हैं, "इसमें कई प्रांतों के लोक संगीत को लोकप्रिय माध्यमों द्वारा दर्शाने की कोशिश की गयी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, बंगाल, राजस्थान आदि प्रांतों की चुनिंदा लोकधुनों के साथ-साथ वहां के लोक नृत्यों को भी चित्रांकित किया गया है। खास बात यह है कि हर नृत्य और गीत उपयुक्त लोकेशनों पर ही फिल्माये गये हैं।"

हरीश तिवारी बतलाते हैं, "सबसे कठिन काम था इन्हें दस या तेरह एपीसोडों में कैद करना। अब आप सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए। इन प्रांतों में लोक संगीत तथा लोक नृत्य में इतनी विविधता है कि सिर्फ एक ही प्रांत के लोक संगीत पर २३-२३ मिनट के २६ एपीसोडों वाले सीरियल बनाये जायें, तो भी वे अधूरे ही साबित होंगे।

लोक धुनों का चुनाव हो जाने के बाद इसे संगीतकार ऋषिराज ने संगीत तकनीक में स्वरबद्ध किया और प्रसिद्ध नर्तक गोपीकृष्ण की शिष्या अरुणा चांदीवाला ने कलाकारों के साथ नृत्यबद्ध किया। हरीश तिवारी बतलाते है, "मैं इन्हें फिल्म जगत के प्रख्यात पार्श्वगायकों से गवा तथा कलाकारों पर फिल्मा भी सकता था, लेकिन माटी की सुगंध अपनी मौलिकता बरकरार रखे, इसलिए इन्हीं क्षेत्रों के एकदम नये गायकों की आवाज में इनकी रिकार्डिंग की। किशन राय, अंजना दत्ता, कुलवंत सिंह, वंशी पुरुषोत्तम, अनिल रामावत, कविता त्रिवेदी, गीता पंत, दीपा नेगी तथा गोदावरी झा की गायन-प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह गोपीकृष्ण के नृत्य स्कूल नटेश्वर से प्रतिभाशाली नृत्यांगनाओं का चुनाव कर उन पर लोक नृत्य फिल्माये।" 'सुरीला हिंदुस्तान' के अधिकांश गायक तथा कलाकार ऐसे हैं जो पहली बार कैमरे या रिकार्डिंग थियेटर में माइक के सामने आये।

लोकगीत के रूप में उत्तर प्रदेश की 'राम लीला' का 'सीता-विवाह' और बिहार की 'गृह पूजा' को 'सुरीला हिंदुस्तान' में विशेष स्थान दिया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र के लावनी तथा राजस्थान के 'इलाची कुमार' लोकनृत्यों को पूरी प्रभविष्णुता के साथ फिल्माया गया है। पंजाब की प्रसिद्ध प्रेम कथा 'हीर' अपने आप में एक नया प्रयोग है। इसकी गायन शैली में परिवर्तन तो नहीं किया गया है, मगर जिन शैलियों में यह गायी जाती है, उनको एक साथ जोड़ दिया गया है। 'हीर' के कवि वारिस शाह के माध्यम से कथा को मार्मिकता प्रदान करने की कोशिश की गयी है। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति की एक रचना को लोककथा गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। मैथिली की गायिका गोदावरी झा ने विद्यापति की इस कठिन रचना को पूरी विविधता से मैथिली में गाया है।

फिल्म जगत के जाने-माने छायाकार प्रताप सिन्हा ने कई जगह छायांकन-प्रयोग भी किये हैं विशेषकर नागा-शिकार नृत्य तथा लावनी नृत्यों एवं गोवानी परंपरा की विवाह कथाओं में। संगीतकार ऋषिराज ने लोक गीतों में भरापन पैदा करने के लिए लोक वाद्यों के साथ-साथ सिंथेसाइजर, स्पेनिश गिटार जैसे विदेशी वाद्ययंत्रों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि लोक संगीत की मौलिकता को नुकसान न पहुंचे। रिकार्डिस्ट अनिल ने भी इस बात पर, रिकार्डिंग के समय, पूरा ध्यान रखा।

हरीश तिवारी बतलाते हैं "मुझे पता है कि इस तरह के सीरियल आम जासूसी तथा कथा प्रधान सीरियलों की तरह आम लोकप्रियता नहीं हासिल कर सकते। लेकिन इस तरह के प्रयास एक प्रांत को दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करते हैं—यह काम भाषा नहीं कर पाती, सिर्फ संगीत ही कर पाता है।"

—रवींद्र श्रीवास्तव

आपके पास प्लाइवुड फर्नीचर है

तो बस भगवान बचाए.

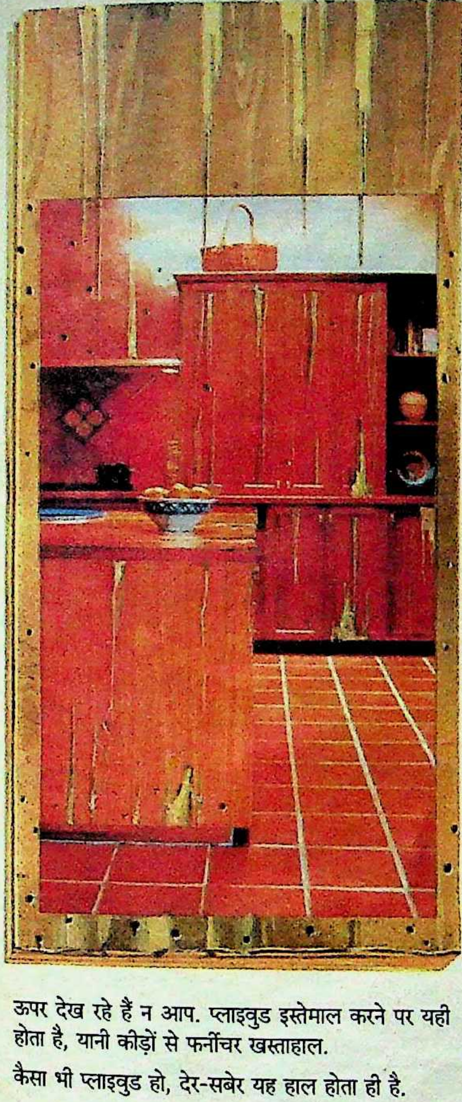

प्लाइवुड की परतें उखड़ती जाए.

प्लाइवुड बेधक कीड़ों से न बच पाए.

प्लाइवुड, स्क्रू को कस कर न पकड़ पाए.

प्लाइवुड को ठोस लकड़ी की तरह तराशा नहीं जा सकता.

ऊपर देख रहे हैं न आप. प्लाइवुड इस्तेमाल करने पर यही होता है, यानी कीड़ों से फर्नीचर खस्ताहाल.

कैसा भी प्लाइवुड हो, देर-सबेर यह हाल होता ही है.

प्लाइवुड बनती ही ऐसे है कि यह सब होना जरूरी है.

लेकिन इस सारे झंझट और नुकसान से बचा जा सकता है.

और अगर नया फर्नीचर बनानेवाले हैं तो समझिए,

खुशी के दिन आए.

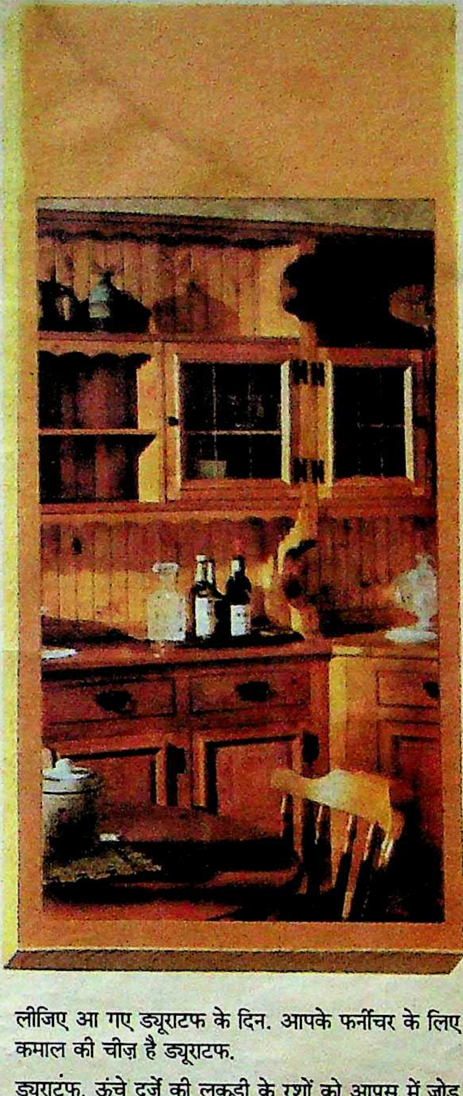

ड्यूराटफ की परतें उखड़ने का सवाल ही नहीं

ड्यूराटफ, बेधक कीड़ों को रखे दूर.

ड्यूराटफ, स्क्रू आदि को खूब मजबूती से पकड़े रहे.

ड्यूराटफ, ठोस लकड़ी की तरह ही तराशा जा सके.

लीजिए आ गए ड्यूराटफ के दिन. आपके फर्नीचर के लिए कमाल की चीज़ है ड्यूराटफ.

ड्यूराटफ, ऊंचे दर्जे की लकड़ी के रेशों को आपस में जोड़ और सुगठित करके एक सिंगल मजबूत बोर्ड के रूप में बनाया जाता है. इसमें परतें होती ही नहीं, इसलिए उनके उखड़ने कासवाल ही नहीं. और बेधक कीड़ों व नमी से यह बराबर बचा रहता है, इसलिए सड़ता-गलता भी नहीं.

और आपको मिलता है सस्ता व सुंदर फर्नीचर जो जीवन भर चलता है.

इसे आप ठोस लकड़ी की तरह ही तराश भी सकते हैं.

ड्यूराटफ, स्क्रू आदि को मजबूती से पकड़ने और जल्द व आसानी से काम आने के लिए खास तौर पर बनाया गया है. इससे कारीगरी का खर्च भी कम बैठता है.

इस बारे में और अधिक जानना चाहें तो हमें लिखकर ड्यूराटफ के उपयोगों की मुफ्त पुस्तिका मंगवाइये.

**अबके फर्नीचर बनाइए
तो कमाल का तगड़ा बोर्ड ड्यूराटफ ही लाइये.**

GENESIS/MT/265

NEW
DURATUFF
THE DURABLE AND TOUGH BOARD

Mangalam Timber Products Ltd.
15, India Exchange Place, Calcutta-700 001. Phone: 201368, 204178/204279. Telex: 0217626, 3355, 3262.
Branches:
Ahmedabad: 77247. Bombay: 2042697/2044378. Bangalore: 74159. Bhubaneswar: 56321. Cochin: 362356. Chandigarh. New Delhi: 730458/ 523408/ 523619.

बछड़े की बरही

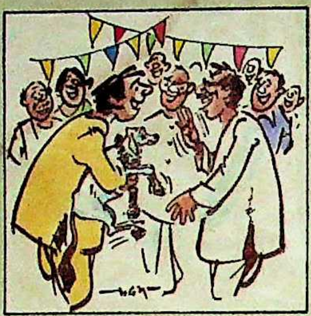

वैसे तो कहने को लड़की-लड़के में कोई भेद नहीं, लेकिन जिनके लड़के न हों, केवल लड़कियां ही लड़कियां हों, उनके दिल का हाल उनसे पूछिए जिनके लड़कियां ही लड़कियां हैं। वे पुत्र की अभिलाषा में एक-के-बाद-एक लड़कियों को जन्म देते चले जाते हैं। तथापि उनसे भी ज्यादा परेशान हाल वे लोग हैं, जिनके कोई संतान नहीं है। कुछ लोग इसके लिए पत्नी को दोषी मानकर दूसरा, तीसरा...विवाह करते हैं। लेकिन फतेहपुर जिले के चांदपुर निवासी मन्नी सिंह ने इस अभाव की पूर्ति के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे सैकड़ों लोगों को न केवल भरपेट सुस्वादु भोजन मिला, बल्कि उनका मनोरंजन भी हुआ।

मन्नी सिंह की बड़ी लालसा थी कि उन्हें कोई पुत्ररत्न प्राप्त हो और वे खूब धूमधाम से उसकी बरही मना सकें। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पायदान पर खड़े मन्नी सिंह की अभिलाषा पूरी न हो सकी। अंततः निराश मन्नी सिंह ने अपनी गाय के बछड़े को ही पुत्र मान लिया और बड़े ही उल्लास और धूमधाम के साथ उसकी बरही की। इस अवसर पर सैकड़ों व्यक्तियों ने भोज खाये और सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया।

सिर में स्क्रू

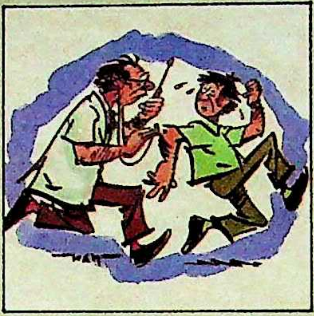

आज इतने अच्छे-अच्छे डाक्टर हैं कि एक बार वे मौत से भी आदमी को निजात दिला सकते हैं, लेकिन कभी-कभी उनसे भी अनजाने ऐसी भूल हो जाती है कि मरीज को लेने-के-देने पड़ जाते हैं। स्वीडन से मिली एक खबर से पता चला है कि एक मरीज के सिर में अड़तालीस सालों से लोहे का एक स्क्रू पड़ा हुआ था।

दरअसल ६२ वर्षीय इस मरीज को पिछले क्रिसमस के दिन एकाएक दाहिने कान के पीछे भीषण दर्द उठा और उसका सिर सूज गया। वह दौड़ा-दौड़ा डाक्टर से मिला। डाक्टर ने उसे एक्स-रे की सलाह दी। जब वह एक्स-रे रिपोर्ट लेकर उससे मिला, तो डाक्टर को काटो तो खून नहीं। क्योंकि उस मरीज के सिर में २५ मिलीमीटर लंबा और मिलीमीटर मोटा एक स्क्रू रह गया था। डाक्टर ने जब उससे पूछना शुरू किया, तब उसे याद आया कि जब वह १४ वर्ष का था, तब एक बार देशी पिस्तौल से खेल रहा था। खेल-खेल में ही वह पिस्तौल दग गयी थी और उसके नाक से काफी खून बहा था। बहरहाल वह अस्पताल गया। वहां डाक्टरों ने दो सप्ताह के अंदर ही उसे स्वस्थ घोषित कर दिया और वह घर चला आया था।

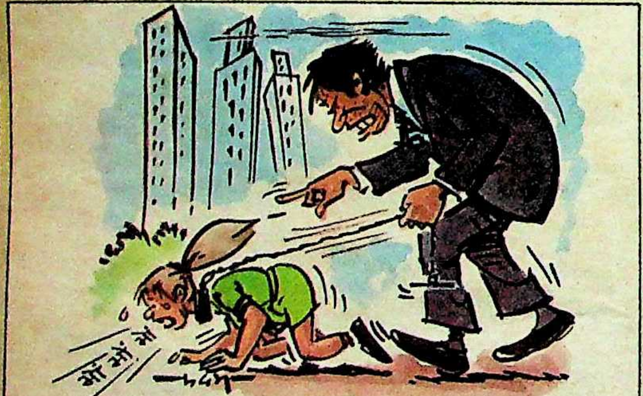

हिटलरी बाप

हर बच्चा अपने मां-बाप के जिगर का टुकड़ा होता है। ऐसे बिरले ही माता-पिता होंगे, जो अपने बच्चों को किसी तरह का दुख देने के पक्ष में रहते हों। लेकिन न्यूयार्क के मि० डिक्सन ने अपनी लड़की को जिस तरह दंडित किया, उससे तो उसे जेल की हवा तक खानी पड़ गयी।

दरअसल, हुआ यह कि मि० डिक्सन की १३ वर्षीय बच्ची एक दिन कहीं चली गयी और किसी कारण से रात में घर नहीं लौट सकी, सो डिक्सन को बहुत बुरा लगा और उसने उसे अनुशासन में रखने का एक नायाब तरीका खोज निकाला। पहले तो उसके गले में एक पट्टा पहना दिया और कहा कि गली में घुटनों के बल भौंकते हुए कुत्तों की तरह चलो। वह बेचारी मजबूर थी, इसलिए क्रूर बाप की हुक्मउदूली तो कर नहीं सकती थी, सो उसने वैसा ही किया जैसा उसके बाप ने चाहा, लेकिन न जाने उसकी इस हरकत की सूचना स्थानीय पुलिस को कैसे मिल गयी, सो पुलिस आ धमकी। पुलिस ने लड़की को छुड़ाया फिर उसके बाप डिक्सन को हथकड़ी पहनाकर थाने लेकर चलती बनी।

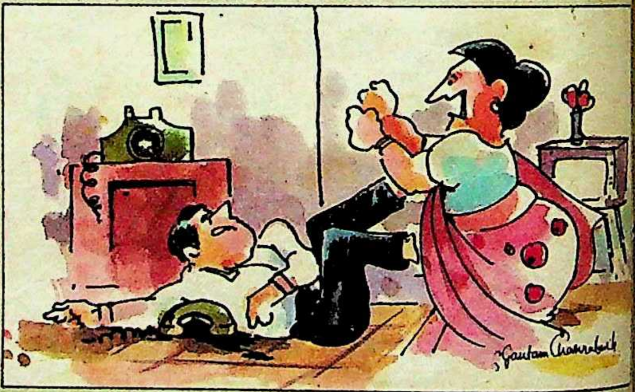

जिसकी बीवी मोटी...

यह बीवी के ही बूते की बात होती है कि वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और घरवालों को स्वर्गवासी भी। पता नहीं अमरीका के ब्रिजपोर्ट के निवासी स्टैनली वाकर का घर उनकी बीवी की वजह से स्वर्ग था या नहीं, लेकिन वह अपनी बीवी की वजह से स्वर्गवासी जरूर हो गये।

खुफिया पुलिस स्काट गार्डन के अनुसार हुआ यह कि ४७ वर्षीय स्टैनली वाकर अपनी मियामी में रह रही मां से टेलीफोन पर बात कर रहे थे कि किसी घरेलू मसले पर उनकी पत्नी श्रीमती वानी वाकर से नोकझोंक हो गयी। हाथापाई में उनकी पत्नी उनके ऊपर गिर गयीं बस वे अचेत हो गये। जब उन्हें सिटी अस्पताल में भरती कराया गया, तो डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गार्डन ने यह तो नहीं बताया कि श्रीमती वाकर का असली वजन क्या था, लेकिन उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि वे जरूरत से ज्यादा वजनी थीं। गार्डन के अनुसार वाकर के दो जवान बेटे और एक छोटा बच्चा भी हादसे के समय मौजूद थे, लेकिन अभी तक वाकर की मौत की असली वजह नहीं पता चल सकी है।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

आम चुनाव

क्या भाजपा का दिल्ली पर वर्चस्व है ?

दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस-इ,
भाजपा और जनता दल के उम्मीदवारों की खोज और जोड़तोड़ भी शुरू
हो गयी है। भाजपा का दावा है कि इस बार दिल्ली से इंका का
सफाया हो जायेगा, मगर कैसे ?

संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के इस्तीफों की मूसलाधार वर्षा के वाद विपक्षी राजनीति में काफी बहार आ गयी है। भारतीय जनता पार्टी काफी गद्गद है कि अगले आम चुनाव में वह दिल्ली में वोटों की भरपूर फसल काटेगी। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल खुराना अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। अपनी संभावित विजय का उनका दावा बहुत रोचक है, "दिल्ली में एक वार कांग्रेस जीतती है, तो दूसरी बार हम। अब हमारी बारी है, क्योंकि १९८४ में सारी सीटें (७) कांग्रेस के पास गयी थीं।"

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल खुराना अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। अपनी संभावित विजय का उनका दावा बहुत रोचक है।

अपनी बारी पर अटूट आस्था की बात तो अलग है, वैसे आपातकाल के बाद पूरे देश में छायी कांग्रेस विरोधी लहर के दौर में हुए १९७७ के आम चुनाव को छोड़ दिया जाये, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 'गढ़' दिल्ली में सभी सातों संसदीय सीटें कभी नहीं मिलीं। यहां तक कि १९६७ के चुनाव में भी एक सीट (बाहरी दिल्ली) कांग्रेस ने हथिया ली थी। फलत: जनसंघ को छह सीटें मिली थीं। जनता पार्टी के शासन काल के उथल-पुथल भरे दिनों के बाद १९८० में हुए चुनाव में उसके एक मात्र दिग्गज नेता अटलबिहारी वाजपेयी ही नयी दिल्ली क्षेत्र से निर्वाचित हो सके थे। वे भी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सीएम स्टीफन से लगभग ढाई प्रतिशत मत ही अधिक पा सके थे। शेष सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बनाये रखा था। उस समय भी मदन लाल खुराना ने जोरदार दावा किया था कि १९७७ का इतिहास फिर दोहराया जायेगा, पर पासा उलटा ही पड़ा और भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा, ब्रज मोहन, किशोर लाल, सिकंदर बख्त, कंवरलाल गुप्त और शिवनारायण सरसोनिया सरीखे दिग्गज नेता जीतने के सपने देखते रह गये।

इतिहास के दोहराव का सपना देखनेवाली भाजपा ने शुरू में दिल्ली की सात सीटों का जनता दल के साथ बंटवारा करना भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वह सातों सीटें जीतने का दावा कर रही थी। खुराना कहते हैं, दिल्ली में बहुत काम किया है और मतदाता से हमारे घरेलू रिश्ते बन गये हैं, जबकि जनता दल की यहां कोई पकड़ नहीं है।" उनका मत है कि दिल्ली में ध्रुवीकरण हो गया है और सीधा मुकाबला भाजपा और जनता दल के बीच होना है।

यह सही है कि कांग्रेस से विमुख होने के बाद दिल्ली के मतदाता भाजपा की ओर मुखातिब होते हैं, लेकिन यह नकारात्मक लाभ है। सकारात्मक लाभ के लिए भाजपा ने पिछले साढ़े चार साल में कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। हां, कुछ महीने पहले से भाजपा ने दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों तथा घनी आबादीवाले क्षेत्रों में घुसकर अपने पुराने रिश्तों में जान फूंकने का प्रयास किया है। अब नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद मचे तूफान से भाजपा को स्थिति मजबूत करने का मौका और मिल गया है।

मन मसोस कर ही सही, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए भाजपा ने दिल्ली को दो सीटें जनता दल को देने का अब मन बना लिया है। पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली की सीट पर जनता दल किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना चाहता है जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त हो और निर्विवाद भी हो।

भगत का मुकाबला: पूर्वी दिल्ली केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हरकिशनलाल भगत की सीट है और भगत 'दिल्ली के बेताज बादशाह' माने जाते हैं। उनके मुकाबले में दिल्ली का कोई विपक्षी नेता टिक नहीं पायेगा। इस कारण विपक्षी यहां से मेनका गांधी या प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी को खड़ा करना चाहता है। शबाना ने बम्बई की झुग्गी-झोंपड़ियों में बहुत काम किया है तथा पंजाब के मसले पर स्वामी अग्निवेश के साथ पदयात्रा करके काफी ख्याति जुटा ली है। पर शबाना दिल्ली से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हैं। वे अपने पैतृक गृह के निकट घोसी (आजमगढ़) में खड़ी होना चाहती हैं। शबाना के स्पष्ट वामपंथी रुझान के कारण भाजपा शबाना का नाम आसानी से नहीं पचा पा रही है। खुराना कहते हैं कि जनता दल अपना उम्मीदवार स्वयं तय करेगा, पर हम चाहेंगे कि इस बारे में हमसे विचार विमर्श अवश्य कर लिया जाये। बाहरी व्यक्ति को यहां से खड़ा करने की वकालत करते हुए एक विपक्षी नेता का कहना है कि यह चुनाव बोफोर्स, भ्रष्टाचार और ईमानदारी जैसे मुद्दों को लेकर लड़ा जायेगा, इसलिए किसी भी साफ छविवाले उम्मीदवार को खड़ा करने में कोई जोखिम नहीं है।

लोग बताते हैं कि भगत के कार्यकर्ता और समर्थक हर जरुरत के समय उपलब्ध रहते हैं और भगत स्वयं छोटी-छोटी बातों की खबर रखते हैं।

मेनका गांधी को पूर्वी दिल्ली से लड़ाने के पीछे तर्क यह है कि उनके पति स्व० संजय गांधी ने दिल्ली के इस हिस्से में झुग्गी-झोंपड़ियां बसवाई थीं। इस कारण इस तबके के मतदाता के दिल में मेनका के लिए खास जगह है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों में लगभग १२ लाख लोग रहते हैं और अधिकांश ऐसी बस्तियां यमुनापार इलाके में हैं। लेकिन मेनका उप्र के लखीमपुर खीरी या पीलीभीत जिलों के किसी

तराई क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं, जहां सिख काफी बड़ी संख्या में बसे हैं। यह बात तो तय है कि सिखों के वोट कांग्रेस के विरोध में ही पड़ेंगे और मेनका को इसका लाभ मिल सकता है। भगत के जोड़ का कोई नेता भाजपा के पास नहीं है। भगत के मुकाबले में खड़े जनता पार्टी के दिग्गज नेता किशोर लाल १९७७ की लहर में जीत गये थे, पर १९८० के चुनाव में उन्हें भगत से लगभग २१ प्रतिशत कम वोट मिले। १९८४ के चुनाव में तो किशोर लाल की हालत और खराब साबित हुई, जब भगत को ७६.९५ प्रतिशत और किशोर लाल को केवल १४.७४ प्रतिशत वोट मिले।

अगर यह सीट भी भाजपा को दे दी जाये, तो वह जेके जैन (अंग्रेजी पत्रिका 'सूर्या' के मालिक) या पंडित यज्ञदत्त शर्मा को खड़ा कर सकती है। पंडित शर्मा पंजाब से दो बार सांसद रह चुके हैं और प्रभावशाली वक्ता हैं, पर वे और जैन दोनों ही भगत के सामने काफी कमजोर रहेंगे। यही कारण है कि यह सीट जनता दल को देने में भाजपा को कोई संकोच नहीं है।

भगत ने अपने संसदीय क्षेत्र में काफी काम किया है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता (१४-१५ लाख) हो गये हैं और जनसंख्या का दबाव यमुनापार इलाकों में अधिक है। भगत ने एक जमाने में दिल्ली से अलग-थलग इस इलाके को सड़कों के जरिए मुख्य भागों से जोड़कर यहां की कीमत बहुत बढ़ा दी है। बिजली और पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करके इन इलाकों के निवासियों को अपने पक्ष में कर लिया है। लोग बताते हैं कि भगत के कार्यकर्ता और समर्थक हर जरूरत के समय उपलब्ध रहते हैं और भगत स्वयं छोटी-छोटी बातों की खबर रखते हैं। अकसर छोटे-मोटे मसले सुलझाने भगत स्वयं पहुंच जाते हैं।

लेकिन इस सबके बावजूद भगत के सामने कुछ दिक्कतें भी हैं। यमुनापार इलाकों में करीब दो लाख मुस्लिम और लगभग सवा लाख सिख मतदाता हैं जो रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और पंजाब में सरकार की भूमिका व दिल्ली में दंगों के कारण भगत की जीत में बाधा खड़ी कर सकते हैं।

झुग्गी-झोंपड़ी और मलिन बस्तियों के बाशिंदों को भगत से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भगत ने पहले प्रति व्यक्ति ८० वर्गगज का भूखण्ड आवंटित करवाने का वायदा किया था जो पूरा नहीं किया गया है और अब भगत उन्हें केवल १२ वर्ग गज का भूखण्ड दिलवाने की पेशकश कर रहे हैं। इससे उन लोगों में रोष पैदा हो गया है।

इसी तरह भगत के कट्टर विरोधी केंद्रीय राज्यमंत्री जगदीश टाइटलर ने भगत की नाक में दम कर रखा है। हालांकि भगत के मुकाबले टाइटलर (जो दिल्ली सदर से सांसद हैं) की पकड़ कमजोर है और उनके समर्थकों की तादाद भी कम है, पर आपसी कलह का फायदा विपक्षी उम्मीदवार को मिलना ही है। इसके अलावा चौ० दिलीप सिंह, हरचरण सिंह, मुश्ताक, शिवचरण गुप्त, हीरा सिंह, दीपचंद शर्मा, चौ० फतह सिंह, अनवर अली देहलवी, विश्वबंधु गुप्त, सुंदरवती नवल प्रभाकर, रामलाल, एएन चावला और मांगे राम भगत की जड़ें खोदने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। चांदनी चौक से इंका सांसद जेपी अग्रवाल के पाला बदलकर टाइटलर गुट में शामिल हो जाने से भी भगत गुट की ताकत कुछ कम हुई है। भगत इन सबसे विचलित नहीं हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में गतिविधियां तेज कर दी हैं, ताकि दिल्ली का 'ताज' उनके सिर से सरक न जाये।

पंत की स्थिति: दिल्ली की दूसरी महत्वपूर्ण सीट नई दिल्ली है। केंद्रीय रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत यहीं से सांसद हैं। पंत इस सीट से दुबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वह उप्र में नैनीताल का अपनी पुश्तैनी सीट पर वापस लौटना चाहते हैं। इंकाई मानते हैं कि अगर पंत को यहां से फिर लड़वाया गया, तो उनका जीतना मुश्किल होगा। इंका की दुविधा यह है कि इस सीट से अब किसको लाया जाये? इंका का एक बड़ा गुट यहां से जगमोहन को खड़ा करने का पक्षधर है जो हाल में जम्मू-कश्मीर के राजभवन से दिल्ली वापस बुला लिये गये हैं। जिस सफलता से जगमोहन ने उथलपुथल भरे जम्मू-कश्मीर में अपना दायित्व निभाया है, उससे उनकी छवि बहुत सुधरी है और दिल्ली की जनता से उपराज्यपाल के रूप में उनके रिश्ते भी अभी फीके नहीं पड़े हैं। लेकिन जगमोहन संसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इंका उच्चकमान उन्हें दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ज्यादा इच्छुक है हालांकि मौजूदा मुख्य कार्यकारी पार्षद जगप्रवेश चंद्र भी इस पद पर अपनी आंख लगाये बैठे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल रोमेश भंडारी नयी दिल्ली सीट से लड़ने के इच्छुक हैं, पर उनका पलड़ा काफी कमजोर है।

जीतना मुश्किल: रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत

भगत के खिलाफ: केंद्रीय राज्यमंत्री जगदीश टाइटलर

विश्वस्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा नई दिल्ली की सीट जनता दल को देने को तैयार हो गयी है। जनता दल ने फिलहाल इस के लिए किसी नाम का फैसला नहीं किया है 'इंडियन एक्सप्रेस' के बहुचर्चित सम्पादक शौरी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएन ग्रोवर नाम इस सीट के लिए चर्चा में है। नई दिल्ली क्षे सरोजिनी नगर, किदवई नगर तथा गोल मा तीन महानगर परिषद क्षेत्रों में अधिकांश सरक कर्मचारी रहते हैं। इनमें लगभग दो लाख मतद हैं जो आमतौर पर सत्ता के विरोध में अपना डालते हैं। उम्मीदवार को लेकर इंका की दुविधा लाभ विपक्ष को मिलेगा और इस क्षेत्र का पढ़ा-लि मतदाता बोफोर्स और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों कांग्रेस के विरोध में वोट देगा।

पहले भाजपा इस सीट से अटलबि वाजपेयी को लड़ाने के पक्ष में थी, पर वाजपेयी या राजस्थान के किसी क्षेत्र से लड़ना चाह क्योंकि वाजपेयी १९८० में इस क्षेत्र से इंका सीएम स्टीफन को हराकर निर्वाचित हुए १९८४ के चुनाव में यहां से भाजपा के कंवरल गुप्त पर से लगभग ३६ प्रतिशत मतों के अंत हारकर दूसरे स्थान पर रहे थे। उनके निधन भाजपा के पास इस क्षेत्र में कोई स्थानीय नेता रह गया है।

भाजपा की प्रदेश इकाई ने अपने राष्ट्र अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से दिल्ली की कि सीट से लड़ने की पेशकश की है, पर आडवाणी ने बारे में अभी फैसला नहीं किया है। भाजपा के की पांच सीटों में से एक महिला उम्मीदवार खड़ा किया जाना निश्चित है। इनमें हरियाणा मंत्री सुषमा स्वराज तथा दिल्ली महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष पूर्णिमा सेठी का नाम जोरशोर से लिया रहा है।

अर्जुन सिंह की जगह: दक्षिण दिल्ली महत्वपूर्ण सीट को लेकर भी इंका पसोपेश में अर्जुन सिंह के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट 'कैम्पा कोला' के मालिक चरणजीत सिंह को करने की चर्चा है, वहीं भगत अपने 'भक्त' मु शर्मा को टिकट दिलाने की जोड़तोड़ में लगे हैं, तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस-इ का अध्यक्ष बनवा दिया है। चरणजीत १९८० में इस सीट से इंका के टिकट पर जीते थे, १९८४ में ललित माकन को टिकट देकर चरण सिंह को मैदान से बाहर कर दिया गया चरणजीत सिंह इस बार अपना दावा इस सीट मजबूत करने को आतुर हैं। इन दोनों के बीच नाम और उभर कर आया है, वह है ललित माक भतीजे अजय माकन का। अपने स्व० चाचा निर्वाचन क्षेत्र में अजय के नाम पर विचार जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्यों आतंकवादियों के हाथों चाचा को मारे जाने सहानुभूति अजय के लिये वोट जुटाने में करेगी। जगमोहन का नाम इस क्षेत्र के लिए चर्चा में था, पर उनकी चुनाव लड़ने की अनिच्छा चर्चा थम गयी है।

पर भाजपा इस सीट पर अपनी नजर गड़ाये हुए है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विजयकुमार मल्होत्रा बताते हैं कि इस सीट के मौजूदा भाजपा पार्षदों में से ओपी वाधवा, जगदीश मुखी, करण सिंह तोमर, रामभज तथा पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद केदारनाथ साहनी का नाम प्रस्तावित किया गया है। साहनी भी संसद का चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, इस कारण फैसला अन्य नामों में से ही होना है।

चांदनी चौक से मल्होत्रा : जगदीश टाइटलर का मुकाबला एक बार दिल्ली सदर क्षेत्र से भाजपा के दिग्गज नेता विजयकुमार मल्होत्रा से होना तय है। मल्होत्रा ने 'माया' से बातचीत में स्वीकार किया कि उनका नाम आम सहमति से तय किया गया है और "केंद्रीय नेताओं के आदेश को वे टालेंगे नहीं।" मल्होत्रा १९७७ के चुनाव में दक्षिण दिल्ली से इंका के चरणजीत सिंह से लगभग ४० प्रतिशत अधिक मत पाकर लोकसभा पहुंचे थे और १९८४ में सिंह से बहुत कम अंतर से हार गये थे। अब वे सदर से टाइटलर से चुनावी दंगल करेंगे। टाइटलर ने इस सीट पर पिछले चुनाव में मदनलाल खुराना को हराया था।

चांदनी चौक क्षेत्र से इंका सांसद जयप्रकाश अग्रवाल को भाजपा के सिकदर बख्त से दो-दो हाथ करने होंगे। बख्त पिछले चुनाव में अग्रवाल के निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे और भारी अंतर से पराजित हुए थे। चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और भाजपा की रामजन्मभूमि संबंधी मुस्लिम विरोधी नीति का असर मुस्लिम मतों पर पड़ेगा, पर ये मत इंका की झोली में भी नहीं जायेंगे। इस क्षेत्र में वैश्य और व्यापारी वर्ग की संख्या बहुत है और भाजपा इन्हीं को अपनी जीत का आधार बनायेगी। बख्त के अलावा सतीशचंद्र खण्डेलवाल, ताराचन्द्र खण्डेलवाल, सत्यचरण बंसल और श्यामचरण गुप्त के नामों की भी संस्तुति की गयी है, पर बख्त के नाम पर सहमति हो गयी है। बख्त के न लड़ने पर इनमे से किसी और नाम पर विचार किया जायेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह राजस्थान छोड़कर दिल्ली की सीट से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और करोलबाग की आरक्षित सीट से वे लड़ने का मन बना रहे हैं। इस सीट से इंका की सुंदरवती नवल प्रभाकर की पकड़ अपने मतदाताओं पर कमजोर हो गयी है और कांग्रेस उनकी जगह किसी सशक्त उम्मीदवार को लाने की सोच रही है। विपक्ष के आपसी बंटवारे में यह सीट भाजपा के हिस्से में है। वहां से वह महानगर परिषद में विपक्ष के नेता कालका दास या सुरेंद्रपाल रथवाल को खड़ा करेगी। कालका दास मजबूत नेता हैं और अपने शांत व संयत स्वभाव के कारण क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं।

बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग पूर्वी दिल्ली के बराबर है। इस जाटबहुल इलाके में भाजपा महानगर परिषद सदस्य चौ० ब्रह्म सिंह, परिषद के पूर्व उपसभापति जनार्दन गुप्त, धरम सिंह सोलंकी और साहब सिंह में से किसी एक को खड़ा करेगी। इंका के चौ० भरत सिंह इस क्षेत्र से सांसद हैं और उनका अच्छा प्रभाव है। इस सीट को कांग्रेस से हथियाना भाजपा के लिए लगभग असंभव है।

प्रतिष्ठा का प्रश्न : केंद्रीय सत्ता की नाक के नीचे की सात सीटों का चुनाव इंका और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा। इंका अपने विकास कार्यक्रमों—जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पंचायती राज और अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और इसी आंधी में बोफोर्स तोप की गरज को दबाने का प्रयास करेगी। इंका महासचिव आस्कर फर्नांडीस तो मानते हैं कि दिल्ली में बाहर से आकर बसे शरणार्थी ही भाजपा के मतदाता थे जो अब पूरी तरह दिल्लीवासी बन गये हैं और वे समझते हैं कि कांग्रेस ही उनके हितों की रक्षा कर सकती है।

कमजोर पकड़ : सुंदरवंती नवल प्रभाकर

जद की चाहत : इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी

फर्नांडीस का तर्क है कि भाजपा जब सत्ता में थी, तब उसने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगी? भाजपा अध्यक्ष आडवाणी तो कांग्रेस से अपनी पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि हवा कांग्रेस के खिलाफ है और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ असंतोष की अभिव्यक्ति इस चुनाव में होगी।

भाजपा के पास कांग्रेस-इ की असफलताओं तथा भ्रष्टाचार का ब्रह्मास्त्र है। इन्हीं को लेकर वह चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। भाजपा की रणनीति है कि १९८३ के दिल्ली नगर निगम तथा महानगर परिषद के चुनाव में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष हरकिशनलाल भगत द्वारा जारी किये गये चुनावी घोषणा-पत्र की प्रतियां जनता में बंटवायी जायेंगी और कांग्रेस को जनता की अदालत में खड़ा करके यह पूछा जायेगा कि पिछले छह वर्षों में उनमें से कितने वायदे पूरे किये गये हैं। भाजपा का मानना है कि यही एक हथियार बोफोर्स बन जायेगा और कांग्रेस का दिल्ली से सफाया हो जायेगा।

इस घोषणा पत्र में दिल्ली को विधानसभा देने, बिक्री कर समाप्त करने, अवैध कालोनियों को नियमित करने तथा नयी कालोनियां बनाने, मलिन बस्तियों का सुधार करने, फुटपाथों पर सामान बेचनेवालों को खोखा देने जैसे ३४ वायदे किये गये थे, जिनको चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने ईमानदारी से भुला दिया। यह वायदा खिलाफी नेताओं के गले में फांसी का फंदा साबित हो सकता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों से दिल्ली के नागरिक सीधे जुड़े हुए हैं। भाजपा इनका भरपूर फायदा उठाने की रणनीति बना चुकी है। अब कांग्रेम अंतिम क्षणों में कौन-सा तुरुप का पत्ता चलेगी—इसको लेकर भाजपा में माथापच्ची हो रही है।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर विधानसभा देने का वायदा पूरा न करने और स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले वर्ष चुनाव की अधिसूचना जारी होने के तीन दिन पहले टाल दिये जाने के सवाल बवंडर बनकर इंका के सामने खड़े होंगे। आडवाणी दावा करते हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव इंका में गुटबाजी की खुफिया रिपोर्ट के कारण टाले गये हैं। अधिसूचना २४ दिसबर, १९८८ को जारी की गयी थी।

खुराना कहते हैं कि हवा अगर कांग्रेस के पक्ष में होती, तो चुनाव कभी नहीं टाले जाते। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हवा माकूल होने पर चुनाव कराने में कतई विलम्ब नहीं किया गया था। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के प्रश्न पर बिठाये गये सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। सूत्रों के अनुसार सरकारिया आयोग ने विधान सभा को कुछ ज्यादा अधिकार देने की संस्तुति की है जो कि इंका हाईकमान को स्वीकार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि गृहमंत्री बूटा सिंह ने गुप्त रूप से यह रिपोर्ट पढ़ ली है, इसी कारण वे सरकारिया को रिपोर्ट पेश करने का समय देने में टालमटोल कर रहे हैं। इंका दिल्ली को मिलनेवाली विधानसभा को कुछ कम अधिकार देना चाहती है।

दिल्ली का विकास बिना विधानसभा मिले संभव नहीं है। भाजपा इसी मसले को अगले चुनाव में जोरशोर से उठाकर इंका की स्थानीय समस्याओं से 'बेरुखी' का पर्दाफाश करेगी।

दिल्ली में ९० लाख लोगों में से ५६ लाख लोगों के पास आम नागरिक सुविधाएं नहीं हैं। इनमें से १५ लाख लोग झुग्गी-झोपड़ियों में, १० लाख लोग पुनर्वास बस्तियों में, १५ लाख लोग अवैध कालोनियों में तथा पुरानी दिल्ली के कटरों में ८ लाख लोग रहते हैं। दिल्ली की सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में १० लाख लोग रहते हैं। रोजमर्रा की तकलीफें झेलते ये लाखों लोग ही अगले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के भाग्य का निर्धारण करेंगे।

—बिशन कुमार

एक दिल्ली यह भी !

देश की राजधानी दिल्ली की आधी से भी अधिक आबादी गंदी बस्तियों में रहती है। लोग तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त, नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए क्यों बाध्य हैं? क्या इसीलिए कि डीडीए के अधिकारी इनके नाम पर लाखों रुपए की बंदरबांट करते रहें? या इसलिए कि ये बस्तियां कांग्रेस-इ के लिए वोट-बैंक बनी रहें?

जब वह वापस लौटा, तो घुप्प अंधेरा था। आधी रात बीतनेवाली थी। उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी जो खिड़की के पास दोनों पैरों को सटाये बैठी थी। उसने दीया जलाया और झोंपड़ी में रोशनी भर गयी। उसने कहा, "मनु, खाना दे साली।" बीवी ने बिना मुड़े टका-सा जवाब दे दिया। वह भी जानता था कि आज भूखे पेट ही सोना है। घास-फूस और मिट्टी से बनी दीवारों, टीन की छत और मात्र छह फुट लंबी इस झुग्गी में वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा तथा अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार किया। कुछ ही समय बाद वह नशे में धुत और बड़े निश्चित भाव से गहरी नींद में पड़ा हुआ था। बीवी ने न तो प्रतिकार किया, न चिल्लाई, न रोई। किसी जादुई सपने में डूबे रहने की तरह वह वहीं निर्वस्त्र पड़ी रही।

बिहार के एक गांव से आकर दिल्ली के १२ लाख झुग्गीवासियों के समुद्र में समा जानेवाले सैनी सिंह के लिए इस दिन जैसी स्थिति आम हो गयी है। इन लाखों रिक्शावालों, पटरी-दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, कबाड़ चुननेवालों और अन्य ऐसे ही काम कर लेनेवालों की तरह वह भी रोज रात अगली सुबह खुशहाल होने के लिए इसी प्रकार 'मरता' है। ये लोग इन्हीं गंदी बस्तियों में शाम को साथ बैठकर गाते-बजाते और किस्से सुनते-सुनाते भी हैं, लेकिन दिल्ली की ऐसी ६०० गंदी बस्तियों का 'गीत' किसी को सुनायी नहीं देता। किसी कवि ने कहा है, 'जिंदगी प्यार और उम्मीद की कविता है।' लेकिन सैनी सिंह कहता है, "ऐसा नहीं है।" उसकी बीवी मनु कोई जवाब नहीं देती। वह रोती और जाने कहां ताकती रहती है।

दिल्ली के मौजूदा विस्तार के आलोचकों का कहना है, "दिल्ली देश का सबसे बड़ा गांव है।" और व्यंग्य के साथ कही यह बात सही भी है। यह शहर जिस तेजी से बहुमंजिली इमारतों का नगर बनता जा रहा है, उसी तेजी से यहां की गंदी बस्तियों का विस्तार भी हो रहा है। शहर की आबादी का ५३ फीसदी हिस्सा, अर्थात करीब ४५ लाख लोग इन्हीं झुग्गी-झोंपड़ियों, गंदी बस्तियों या पुनर्वास कालोनियों में रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी बस्ती है, शहर की 'नाक' माने जानेवाले हिस्से दक्षिणी दिल्ली के बीचोबीच बसा नवजीवन कैंप। ४० एकड़ जमीन पर फैली इस बस्ती में १०,००० झुग्गियां हैं, जिनमें ५०,००० लोग रहते हैं।

बेहिसाब बढ़ती आबादी : १९८१ में दिल्ली की आबादी ६२.२० लाख थी। इसका ३१.४ फीसदी हिस्सा झुग्गी-झोंपड़ियों में रहता था। पचास, साठ और सत्तर के दशक में दिल्ली की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और प्रत्येक दशक में वृद्धि दर ५३ फीसदी रही है। यह देश में आबा कुल विस्तार की दर के दोगुने से भी अधिक है। की आबादी में प्रति दशक २५ फीसदी की वृद्धि रही है। आजकल दिल्ली की आबादी में प्रतिव लाख की बढ़ोतरी हो रही है और उम्मीद है आनेवाले वर्षों में यह वृद्धि तीन लाख प्रतिवर्ष

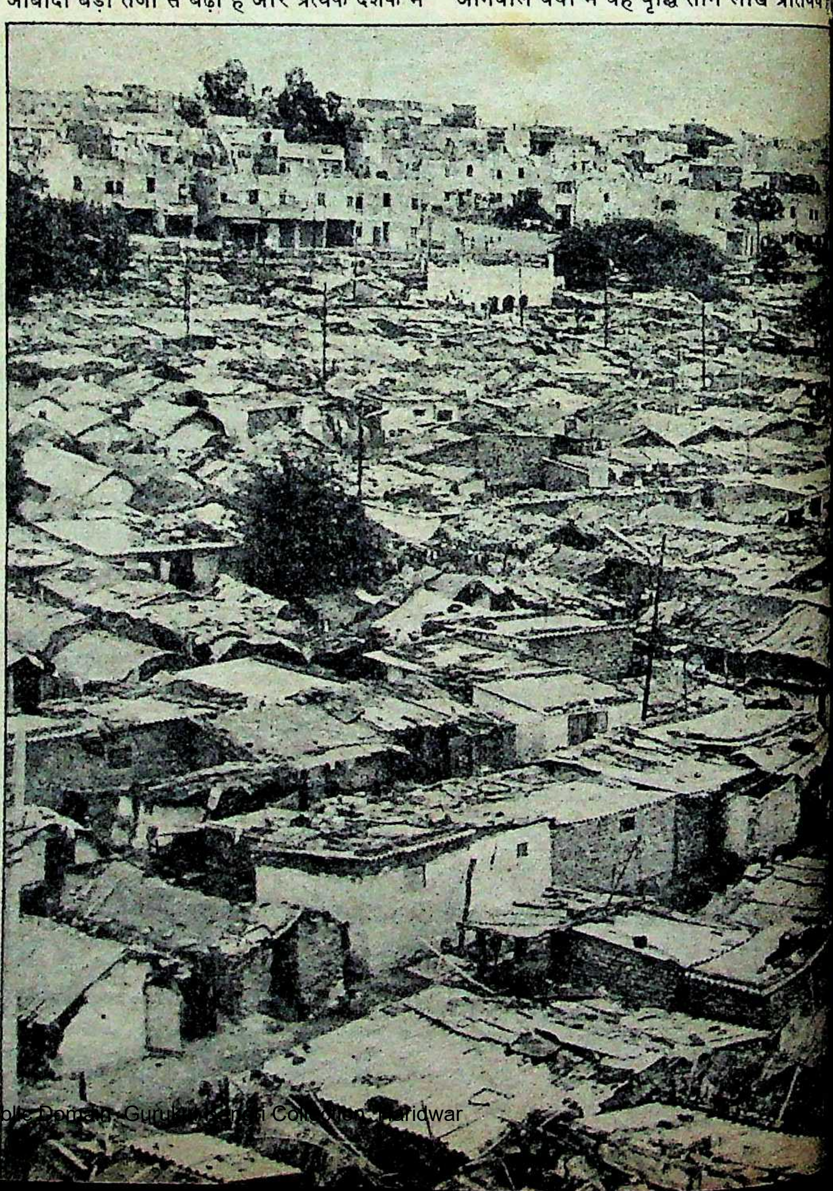

लगेगी। एक अनुमान के अनुसार १९९० में देश की राजधानी की आबादी ९७.६७ लाख हो जायेगी, जिसमें से अकेले ३२.०८ लाख लोग, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहेंगे और करीब इतने ही पुनर्वास कालोनियों में। दरअसल, दिल्ली में आबादी बढ़ने की शुरुआत १९४७ में ही हो गयी थी, तुरंत आजाद हुए देश की इस नवजात राजधानी में पाकिस्तान से भागकर आनेवाले शरणार्थियों की बाढ़ ने यहां के रंग-ढंग को ही बदल डाला। रातोंरात दिल्ली शरणार्थी शिविर में बदल गयी। लेकिन बरसों साथ रह जाने पर यह विस्थापित आबादी स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिलकर एक जैसी बन गयी थी। लेकिन इस बीच एक अन्य बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। वे तो इन वर्षों में समृद्ध व्यवसायी बनकर शहर की आबादी का प्रमुख वर्ग बन चुके थे, लेकिन उन्होंने शहर में झुग्गी-झोंपड़ी डालकर जैसे-तैसे दिन काटने वाली 'परंपरा' डाल दी थी और इसे देश के अन्य भागों से राजधानी पहुंचनेवाले लोगों ने अपना लिया था। विभाजन के कुछ समय बाद १९५१ में दिल्ली में १२७४९ झुग्गियां थीं जो १९५६ में बढ़कर २२४१५ और १९६१ में ४२३१२ हो गयीं और अब तक इनकी संख्या दो लाख तक पहुंच गयी है। इस आबादी का ५० फीसदी से भी अधिक हिस्सा हरिजनों का है, इससे यह बात साबित होती है कि गांवों में आज भी हरिजन-उत्पीड़न थमा नहीं है, लेकिन विस्थापन की इससे भी बड़ी वजह गांवों में काम न मिल पाना है।

जोधपुर, राजस्थान के एक गांव से आकर दिल्ली की गौतमपुरी झुग्गी बस्ती में बसे एक हज्जाम ने बताया, "साहब हम भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रह सकते थे? एक बाल्टी पानी लेने के लिए १० मील जाना कितने दिनों तक चल सकता था? जमींदार ने हमारी छोटी-सी जमीन ले ली। मैं हज्जाम हूं और वहां रहते हुए मैं कभी भी नकद कुछ नहीं कमा पाया। जमींदार से लेकर किसान तक हमें साल में दो बार चावल और गेहूं देते थे। इस तरह गांव में अभी भी बढ़ई से लेकर सभी पेशे के लोगों को मजदूरी के बदले अनाज मिलता है। ऐसा करके कितने दिन चल सकता है?"

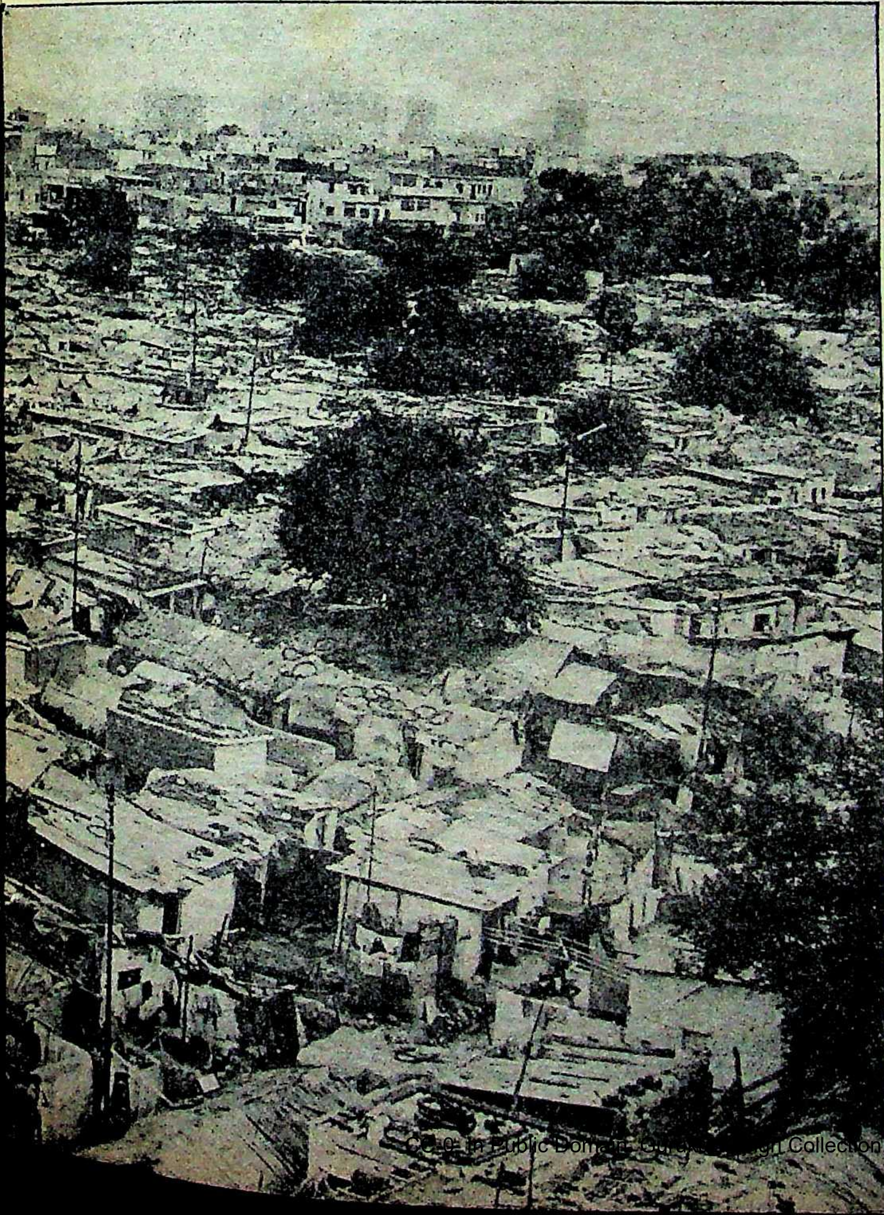

छाया: एस पाल

दिल्ली आनेवालों में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं रहती जो खेती का काम न होने पर शहर भाग जाते हैं। गर्मियों में अनाज कटने के बाद और सर्दियों में खरीफ की फसल के बाद दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इस समय पश्चिमी उप्र, पंजाब, हरियाणा वगैरह की ग्रामीण आबादी का एक हिस्सा कुछ कमाई कर लेने के लिए दिल्ली आ जाता है और दो महीने के बाद गांव लौट जाता है। लेकिन गंदी बस्तियों में टिक जानेवाली आबादी का मुख्य भाग दूर-दराज से आये लोगों का है, जिन्हें यहां अपने गांवों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नगर योजना विभाग के आर्थिक सलाहकार कमल किशोर का मानना है, "भूख की मार इतनी जबरदस्त होती है कि अपनी जमीन और गांव से जुड़ाव एक झटके में ही टूट जाता है। खून का रिश्ता और पुरखों का पेशा छोड़ने में कोई समय नहीं लगता और फिर बेहतर जीवन की तलाश में झुंड-के-झुंड लोग एक नरक से दूसरे नरक में, गांव की भुखमरी से उठकर शहर की गंदगीभरी गंदी बस्तियों में पहुंच जाते हैं।"

दुश्चक्र : मोती राम ने भी ऐसा ही किया था। अपने बाप के दबाव देने पर मोती राम अपने तीन किशोर भाइयों के साथ २५ साल पहले दिल्ली आया था। उसके पास कोई भी खास मूल्यवान चीज नहीं थी। एक जोड़ा धोती, एक स्टोव, एक टूटी-फूटी टीन की पेटी, अल्यूमिनियम के कुछ बरतन, एक लोटा, चार भूखे पेट, कुछ सपने और ढेर सारी उम्मीदें। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भूखे पेट सोने से लेकर कबीरपुर की गंदी बस्ती में पहुंचने में एक महीने का समय लगा। अन्य लोगों को इस काम में अधिक समय लगता है। उनके पास एक पखवाड़े से अधिक तक चलने लायक पैसे नहीं थे और नौकरी पाना तो दूर की कौड़ी हासिल करने जैसा था। दिन गुजरते जाने के साथ ही उनकी बेचैनी बढ़ती गयी। लेकिन दिल्ली में सोना भी कंकड़ के साथ बिछा है और आपको इसे चुनना आना चाहिए। उन लोगों ने भी महीने भर के अंदर यह गुण सीख लिया। उन्होंने दिल्ली की चाय की एक दुकान पर पांच रुपए रोज की मजदूरी करने के साथ ही यह जान लिया कि किस तरह प्रभावशाली दोस्त उन्हें निर्माण कार्यों में मजदूरी दिला सकते हैं, झुग्गी बनाने के लिए कर्ज दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें महीने-महीने 'भुगतान' करना होगा। इस पर शहरी चकाचौंध से चमत्कृत, असंगठित, और अनपढ़ लोग अनजाने में शहरी सूदखोरों, गंदी बस्तियों के माफिया सरदारों, राजनीतिक दलालों, नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करनेवालों और अपराधियों के चंगुल में फंसकर नरकरूपी बस्ती के जीवन को और भी नरक बना लेते हैं। और जब तक मोती राम को इस बात का पता चलता, तब तक उसे स्पष्ट हो गया था कि

अब उसका इस नरक से निकल पाना मुश्किल है।

सरकारी नजरिया: सरकार मानती है कि गंदी बस्तियां शहरी जीवन का अभिन्न अंग हैं और इनका उपचार विकास कार्यक्रमों में निहित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के निदेशक एसी सेठ ने कहा, "हम कानूनी रूप से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं रोक सकते। औद्योगिक विकास के शुरुआती दौर में सभी देशों में शहरों में गंदी बस्तियां रही ही हैं। भारत के साथ भी यही हो रहा है। अगर इसके लिए किसी को दोषी करार देना है, तो यह व्यवस्था ही दोषी मानी जायेगी। इसका चुटकी बजाकर कोई समाधान नहीं कर सकते।" दिल्ली के एक प्रमुख सरकारी संगठन का यह टरकाऊ रुख बहुत परेशानी पैदा करनेवाला है। यह सही है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए गांवों की हालत सुधारनी होगी, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गंदी बस्तियों के नारकीय जीवन में थोड़ा-सा भी सुधार लाने के लिए जरूरी कुछ भी तो नहीं किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के आयुक्त मनजीत सिंह ने दावा किया कि दिल्ली की सभी ६५० गंदी बस्तियों में पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, और करीब-करीब पूरी तरह स्वास्थ्यकर माहौल बना दिया गया है। लेकिन स्वतंत्र रूप से किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गंदी बस्तियों में रहनेवाले लाखों लोगों में से मात्र २० फीसदी के लिए ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो पायी है। शेष लोग वही बीमारी के जीवाणुवाले हैंडपंप का पानी पी रहे हैं। १९८८-८९ में दिल्ली की २०० गंदी बस्तियों में किये गये एक अन्य स्वतंत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि यहां के ४७०८ लोगों को पोलियो, १६०७१ को टीबी था तथा सिर्फ पिछले एक वर्ष के दौरान ४०२ लोग प्लेग से मरे। गैरसरकारी सर्वेक्षणों के और निष्कर्षों के आते जाने के साथ ही यह भयावह सचाई और भी नंगे रूप में सामने आती जा रही है। दूसरी ओर, दिल्ली विकास प्राधिकरण इन मौतों और महामारियों के बारे में सूचनाएं देने से इनकार करता है। जबकि असलियत यह है कि १२ लाख झुग्गीवासियों का मात्र दो फीसदी हिस्सा स्वच्छ कहे जा सकनेवाले क्षेत्र में रहता है, सिर्फ पांच फीसदी को ही कामचलाऊ स्वच्छता नसीब है और वह भी सिर्फ नयी दिल्ली के इलाके में बसे झुग्गीवालों को ही। सिर्फ तीन गंदी बस्तियों—संजय कालोनी, गौतमपुरी और आजाद कालोनी में स्कूल की इमारत है और इन स्कूलों में पढ़ानेवाले शिक्षक कम हैं, व्यवसायी अधिक और यहां जितने बच्चे जुटते हैं, उनसे कई हजार गुना मक्खियां और मच्छर। सभी गंदी बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ६८ फीसदी बच्चे मारक बीमारियों से ग्रसित हैं और २० वर्ष से ऊपर आयु के करीब ९६ फीसदी लोग इस पृथ्वी पर होनेवाले किसी-न किसी रोग की चपेट में हैं। आप अल्सर से लेकर टीबी, पोलियो से लेकर आंत्रशोथ, यौन रोगों, पेट की गड़बड़ी, कोढ, पायरिया से लेकर चेचक तक किसी बीमारी का नाम लीजिए और आपको उसका एक-न-एक मरीज जरूर मिल जायेगा। मानसून आया नहीं कि ये बस्तियां अक्षरश: बजबजा जाती हैं। गंदगी और बदबू का 'राज' कायम हो जाता है। पांच फुट तक उठी ये झुग्गियां इसी गंदगीवाली बाढ़ में डूब जाती हैं। बच्चे इसी पानी में छप-छप करते रहेंगे, कुछ बीमारियां ले आयेंगे और फिर मरने के लिए लाइन लगा देंगे। १९८७ में आयी बाढ़ के समय ठीक यही बात हुई थी।

नसीब ने जो बख्शा है: यमुना झुग्गी बस्ती में रोगाणुयुक्त पानी लेते बंगलादेशी

छाया: ए

इंका के लिए इन लोगों के प्रति सहानुभूति जताने का यही मौका है। वह तब इनके लिए कामचलाऊ शिविर लगाती है, मुफ्त राशन-दवा की व्यवस्था करती है और 'जनसेवा' पर कुछ करोड़ खर्च करके संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि गंदी बस्तियों में रहनेवाले लोग ही तो इसके सबसे बड़े वोट बैंक हैं। साल में एक बार 'आम जनता' के बीच जाने का मौका प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और स्लम आयुक्त नहीं छोड़ते। वे बहुत ही निष्पाप भाव से इन गंदी बस्तियों के भीतर जायेंगे, कुछ राहतों की घोषणा करेंगे और लोगों की तालियां तथा दुआएं बटोरकर चल देंगे। लेकिन कबीरपुर की दस फीट गहरी नाली का कचरा १७ वर्षों से यूं ही पड़ा रह जायेगा और सुंदर नगर नाम तथा नरक जैसे कामवाले मुहल्ले की गंदगी जस-की-तस बनी रहेगी। क्योंकि गंदी बस्तियां तो शहर भर के खुले कूड़ेदान हैं ही। एक गंदी बस्ती में रहनेवाला २० वर्षीय अश्विनी कुमार कहता है, "हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। पुरुष अपनी बीवी से एक झड़प करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद से तनाव रहता ही है।" बस्ती की औरतें खुद भी दिहाड़ी पर काम करती हैं, घरों में झाड़ू-बहारू का काम करती हैं या अपना जिस्म बेचकर जिंदा रहने के लिए पैसा कमाती हैं।

गिरोहों के चंगुल में: ये औरतें बड़े गिरोहों के लिए भी भाड़े पर उठती हैं। इन गि को शहर के बड़े राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त झुग्गी-झोंपड़ी मोर्चा के जवाहर सिंह इस बा काफी कुछ बताते हैं। उनका कहना है कि औरत धंधे के अलावा एक अन्य तरह का धंधा भी च है। कुछ 'राजनीतिक कार्यकर्ता' जमीन पर अ कब्जा करने, झुग्गियों को भाड़े पर देने, फर्जी रा कार्ड बनवाने, इन बस्तियों में रहनेवालो पुनर्वासवाली परची खरीदने और उसे मुनाफे बेचने का काम करते हैं और इन कार्यों से लाखों कमा रहे हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि इन्हें केंद्रीय मंत्रियों तथा पुलिस आयुक्त तक का सं प्राप्त है। साथ ही गुंडों का गिरोह तो सदा उ मदद के लिए तत्पर रहता ही है। जवाहर बताते हैं कि ये दलाल और गुंडे भी इन गंदी-बस्ति में रहनेवालों की तरह ही एक दिन धोती- लेकर दिल्ली आये थे। इन्हीं में से कोई गोपी ठेकेदार बन गया और गैर शाह दुकानदार सूदखोर। गोपी राम ने १९८० के चुनाव चरणजीत सिंह तथा १९८३ के नगर निगम चु में देसराज छाबड़ा के लिए काम किया था। वह भी प्रभावशाली कांग्रेसी नेता हो गया है। गोपी की तरह ही नेपाल से आया नंदर सिंह, हरिया आया तौबत राम, छतरपुर से आया राम साहेब प्रभावशाली नेता है।

आरोप है कि ये लोग बस्तियों के स्वयं प्रधान भी हैं। इन लोगों को ५०० रुपए का च चढ़ाये बिना कोई भी आदमी इन बस्तियों में झु नहीं डाल सकता। प्रत्येक तीसरे महीने दि विकास प्राधिकरण की ओर से हरेक झुग्गी का का सर्वेक्षण होता है और उस समय भी नये लोगों को इन तथाकथित प्रधानों को १०० रुपए

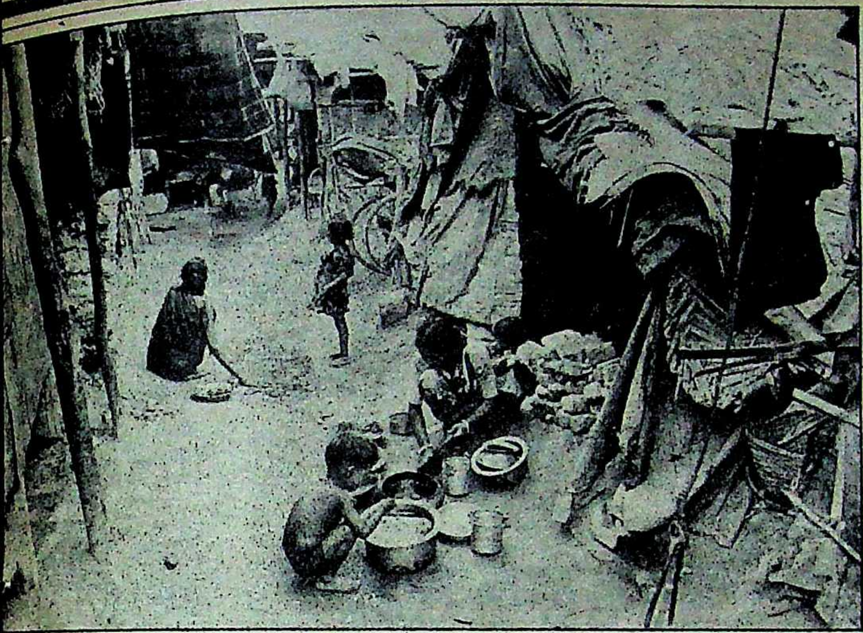

रक की गुफा: यमुना स्लम का मुख्य मार्ग

छाया: एस पाल

ाते हैं, जिससे उनका नाम भी प्राधिकरण की ाइलों में दर्ज हो जाये या उनका राशन कार्ड न न जाये। यही प्रधान इन गरीब लोगों को दिल्ली कास प्राधिकरण की कालोनियों में जगह दिलाने नाम पर पैसा वसूलते हैं।

गिरोहों के संरक्षक: पुलिस और इन याकथित प्रधानों के बीच के रिश्ते के बारे में यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बड़े पुलिस धिकारी तो इस तरह के रिश्ते से इनकार करते हैं। र नीचेवाले इसे स्वीकार करते हैं। जवाहर सिंह ाते हैं, "नारायण सिंह यादव, राजू, पृथ्वी सिंह ार सलीम ने इसी तरह मंगोलपुरी और ल्तानपुरी से काफी पैसा जुटाया। और समयपुर ा नारायण सिंह यादव रातोरात लाखों से खेलने गा है। उसने मजदूर यूनियन का झंडा उठाकर ३५ जार बिहारी झुग्गीवासियों से पैसा जमा किया है। सी प्रकार मायापुरी, नारायणा, कीर्तिनगर, मा रोड, किशनगंज और अन्य स्थानों पर झुग्गियां लकर उन्हें बेचने और अन्य धंधा करके मास्टर जेंद्र ने भी लाखों रुपए कमाये हैं। कुछ झुग्गी स्तियों में आतंक का राज कायम करनेवाले लदेव, जगदीश, कुच्छी और कपिल जैसे गुंडा-रदारों को भगत का संरक्षण प्राप्त हैं।"

जवाहर सिंह का कहना है कि डीएन तिवारी, न्नू सिंह, विमला नेगी और मदनलाल जैसे लोग मीन पर कब्जा करने और बेचने का धंधा करते । इनके दलाल उन लोगों से दिल्ली विकास धिकरण द्वारा झुग्गी तोड़ने के समय दी गयी ची खरीद लेते हैं। यह परची आगे पुनर्वास का वा करने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही र्वास परचियां भी खरीदी जाती हैं। इनकी कीमत ०० रुपए तक दी जाती है और बाद में इन्हें ापारियों और पैसेवालों के हाथ ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार जो कालोनियां झुग्गी बस्तियों से हटाये गये लोगों के लिए बसती हैं, वहां पैसेवालों और व्यापारियों का कब्जा हो जाता है।

झुग्गी टूट जाने पर यह परची भी बेचकर ये झुग्गीवासी फिर सड़क पर आ जाते हैं और फिर से कहीं और जाकर झुग्गी डाल लेते हैं। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है, रोहिणी विस्तार में बसी पुनर्वास कालोनी। जवाहर सिंह का कहना है, "पूठकलां गांव में बसी इस कालोनी के ७० फीसदी प्लाट इंका के सज्जन कुमार और तदबीर सिंह यादव ने खरीद लिये हैं। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण की चुप्पी सबसे अधिक खलती है, जबकि सारा खेल उसकी आंखों के सामने ही चल रहा है।" प्राधिकरण के एक अधिकारी स्वीकार करते हैं, "हां, राशन कार्ड और झुग्गी तोड़ने के बाद दी जानेवाली परची की खरीद-बिक्री के मामले सामने आये हैं, लेकिन वे लोग खुद ही इन्हें बेच देते हैं।" इसका सीधा-सा जवाब है, "भूख के कारण।" मनजीत सिंह ऐसे आरोपों को सीधे ही गलत करार देते हैं और इसके लिए सबूत पेश करने को कहते हैं। लेकिन यह जगजाहिर तथ्य है कि जब राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस का गठबंधन हो जाता है, तो सबूत तो उनकी जूतियों के नीचे आ जाते हैं।

३ अप्रैल, १९८९ को सुबह लोकनायक कैंप से उजाड़े गये कुछ सौ लोगों को लेकर हरि राम तिवारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भगत के घर गये। वे चाहते थे कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाये और इन लोगों के नाम भी नयी पुनर्वास सूची में शामिल कर लिये जायें। लेकिन वे भगत से मिल पायें, इससे पहले ही तीन प्रभावशाली कांग्रेसी नेता—विमला नेगी, मदनलाल और डीएन तिवारी वहां पहुंच गये और सीधे भगत से मिलकर उनसे अपनी उस सूची के लिए सिफारिश करा ली, जिसमें कांग्रेस को वोट देनेवालों के नाम तो थे, लेकिन बहुत से नाम फर्जी भी थे। यह किस्सा एक झुग्गीवासी ने ही बताया और इसे सुनाने के बाद उसने पूछा, "हम कहां जायें? नेता हमें लात मारते हैं, पुलिस धमकाती है और प्रधान लूटते हैं।"

लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका है? महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की एक रिपोर्ट के अनुसार, "प्राधिकरण का स्लम विभाग काफी बड़ा है और अनेक काम इसके जिम्मे हैं। अनेक योजना और गैर-योजना मामलों पर यह काफी धन खर्च करता है। इस पूरे खर्च का आडिट नहीं होता जो बहुत ही आपत्तिजनक बात है।" कोष में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोपों के चलते स्लम आयोग ने गंदी बस्तियों के माहौल में बदलाव की जो योजनाएं बनायी थीं, वे भी नहीं चल पायीं। (देखें बाक्स)

हालात निश्चिंत रूप से ही बुरे हैं। लोगों को अपने नागरिक अधिकारों का भी पता नहीं है। लोगों के इस अज्ञान का राजनेता फायदा उठाते हैं। आरोप है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पैसे में हेरफेर कर लेता है, कानून के रखवाले मौके का अधिक-से-अधिक फायदा उठाते हैं, योजना बनानेवालों को कुछ समझ नहीं आ रहा और दिल्ली अपनी मौत की ओर बढ़ती जा रही है। स्लम आयुक्त मनजीत सिंह गुस्से से कहते हैं, "हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम और अधिक कर ही क्या सकते थे? पर्यावरण सुधार की अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं, गलियों में बिजली लगाने, कम्युनिटी हाल, स्कूल, समाज कल्याण केंद्र और ओपन एयर थिएटर बनाने की ५३९ योजनाएं चल रही हैं, २०५५० मीटर लंबी नालियां, १२२००७ मीटर लंबे नाले (बाढ़ का पानी निकालने के लिए), ५ लाख वर्ग मीटर सड़क और खड़ंजे बिछाने का काम चल रहा है। गंदी बस्तियों में रहनेवाले लोगों में से ९ लाख को छठी योजना की समाप्ति तक फायदा दिया जा चुका है। सातवीं योजना के दौरान ऐसे ८.६० लाख और लोगों के लिए २० करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की रिपोर्ट में इन चीजों पर गौर ही नहीं किया गया है। ये लोग मेरे कमरे में आरोपपत्र और आरोपों का पुलिंदा लेकर जब भी आयेंगे, तो मैं जो जवाब दूंगा उसके बाद वे चुपचाप निकल जायेंगे।"

राजनीति की भूमिका: गंदी बस्तियों की राजनीति भी अजीब है। विपक्षी पार्टियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गयी विभागीय योजनाओं का विरोध करती हैं। उन्हें लगता है कि शासक दल गंदी बस्ती में रहनेवालों को प्रलोभन दे रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस विकास कार्यक्रमों की जगह थोड़ा बहुत पैसा लुटाकर और शराब बहाकर वोट खरीद लेना चाहती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के छोटे अधिकारी गंदी बस्तियोंवाले काम को किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं करते। बड़े अधिकारियों को जब समस्या की गंभीरता का भी अंदाजा नहीं मिल पाता, तो वे

दिविप्रा
(स्लम विभाग)
आपत्तिजनक हिसाब-किताब ?

महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के खर्चों की जांच करके जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें अनेक अनियमितताओं का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है, "१९८७-८८ के दौरान दूकान/खोखे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाने पर जो धनराशि खर्च की गयी, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं। चूंकि बैलेंस शीट तथा आय और व्यय का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया इसलिए इन कामों की प्रगति की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह एक गंभीर गड़बड़ी है, क्योंकि सही पंजियों के अभाव में क्या खर्च हुए इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती।"

रिपोर्ट ने स्लम विभाग की इस बात के लिए भी खिंचाई की है कि उसने तय राशि खर्च नहीं की है और इस प्रकार पैसे के उपयोग के बारे में संदेह पैदा होता है। ४३.३३ करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं किये जा सके। दूसरे शब्दों में कहें, तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुदान की आधी रकम ही खर्च की जा सकी। विकसित भूखंड देनेवाली योजना के लिए ११.५७ करोड़ रुपए रखे गये थे, जबकि मात्र ६५००० रुपए का इस्तेमाल हुआ। इसी प्रकार गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार के लिए रखे गये २६.१० करोड़ रुपए में से १३.४४ करोड़ रु० का ही उपयोग हो पाया। इन चीजों से स्पष्ट लगता है कि स्लम विभाग के पास इन अनुदानों का उपयोग करने के लिए पक्की योजनाएं नहीं हैं।

जैसे, पर्यावरण सुधारवाले अनुदान को ही लें। इस मामले में दिल्ली प्रशासन ने विभाग को २०१०.२३ लाख रुपए दिये थे, जिसमें से १३४४.१२ लाख रुपए का उपयोग हुआ। यह पैसा जल आपूर्ति, नाली, स्नानघर, पाखाना-घर वगैरह बनाने पर खर्च हुआ। लेकिन विभाग ने कहीं भी साफ-साफ नहीं बताया है कि कितने स्नानघर, पाखानाघर बने और कितने इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई तथा कहां कितनी नालियां डाली गयीं। अन्य योजनाओं के मामले में भी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुदान और ऋण से चलनेवाले इस विभाग में यह बात बतानेवाले आंकड़े भी नहीं हैं कि पैसे का सही उपयोग हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कामकाज पर इससे अधिक खराब रिपोर्ट आ नहीं सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "जीएफआर के नियम १५१ (१) के अनुसार प्रत्येक अनुदान खास काम के लिए खास-खास शर्तों के साथ दिया जाता है। ये शर्तें एक भी मामले में पूरी नहीं हुई हैं। जो राशि नहीं खर्च हुई, उसे बिना कुछ सफायी दिये लौटा दिया गया। दिल्ली प्रशासन ने भी इन शर्तों के पालन के लिए कोई कड़ाई नहीं की है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विभाग विभिन्न कामों और विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करता रहा है, लेकिन उसने इस खर्च से हुए काम का कोई ब्यौरा ही नहीं रखा है। रिपोर्ट में कुप्रबंध का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। १९८५ में प्राधिकरण के स्लम विभाग ने झुग्गी-बस्तियों के लोगों तथा अन्य लोगों के लिए आवासीय फ्लैटों के पंजीकरण की योजना शुरू की। इसके लिए प्रत्येक अरजी के साथ ३००० रुपए जमा कराने थे। यह योजना दिसंबर, १९८५ से, जनवरी १९८६ तक खुली थी। २७६०३ लोगों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया। इनसे पंजीकरण शुल्क के तौर पर ८९०.८१ लाख रु० जमा कराए गये। पंजीकरण के बाद पिछले तीन वर्षों से ये लोग जल्दी-से-जल्दी अपना फ्लैट पाने की आस लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनेक कानूनों का उल्लंघन हुआ है। घाटे व पैसों की हेराफेरी का कागजों में जिक्र नही किया गया है, कुछ अधिकारियों की हवाई यात्रा को उचित अधिकारी ने मंजूरी नहीं दी है और स्लम विभाग की गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है और वह आडिट के लिए उन रिकार्डों को देना नहीं चाहता है, जिनसे उसके यहां हुई अनियमितताएं उजागर हो जायें। स्लम विभाग के १९८७-८८ के वार्षिक हिसाब-किताब की जांच करते समय यह पाया गया कि एकाउंट और कैश बुक के बैलेंस में २.८ लाख रुपए का अंतर है। १९८६-८७ और १९८५-८६ तथा उससे पहले के वर्षों के हिसाब-किताब में भी इस तरह की गड़बड़ी पायी गयी। २३ सितबंर, १९८८ को जारी आडिट मेमो नं० ८९ में विभाग से पूछा गया था कि किस वर्ष के हिसाब-किताब से इस तरह का अंतर आ रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब नही मिला। दरअसल, विभाग इस तरह के अंतर का कारण और इसकी शुरुआत के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। यह मामला बहुत गंभीर है और इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। ■

'सोशियो-साइक्लोजिक ओरिएंटेशन प्रो
चलाने की बात करने लगते हैं। और झुग्गी
सत्तारूढ़ कांग्रेस का विरोध करके अपनी झुग्गी
रोजगार दोनों से हाथ धो बैठने का जोखिम
उठा सकते।

दिलचस्प तथ्य यह है कि जिन दो सौ
बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से ७५
इंका का 'राज' ही है। ७९ में उसके और भा
जनता पार्टी के लोगों के बीच टकराहट है।
दल का असर २५ तथा कम्युनिस्ट पार्टियों का
मात्र ७ गंदी बस्तियों तक ही सीमित है। इन
बस्तियों को देखें, तो वर्ग संघर्ष की बात तो
हवाई ही लगती है। यहां के लोगों का दिमा
धार्मिक उन्माद, कठमुल्लापन, राजनीतिक सं
देनेवालों के हिसाब से तय होता है। वे तो सदा
और डरे रहते हैं। उनकी झुग्गियां तो दिल्ली वि
प्राधिकरण और राजनीतिक आकाओं
'कृपादृष्टि' पर ही टिकी रहती हैं। जिस दिन
लोगों की दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन झु
पर बुलडोजर चढ़ जाते हैं। फिर सामान और
की कौन कहे, जान के लाले पड़ जाते हैं। पिछले
वर्षों में ६० हजार झुग्गी-झोंपड़ियों को
तरह उजाड़ा जा चुका है और फिर १९८६
१६ गंदी बस्तियों को तोड़ दिया गया। इन
गये लोगों में से केवल २० हजार को पुनर्वास
किया गया। शेष ४० हजार इस भव्य राजधा
दरबदर नागरिकों की तरह मारे-मारे फिर
गत वर्ष ५० हजार झुग्गीवाले बाढ़ की चपेट में
थे, जिनमें ३० हजार अभी भी दर-दर भटक
अकसर इन्हें नगर के सुंदरीकरण तथा सार्व
इमारतों के निर्माण के नाम पर उजाड़ा जा
और इससे व्यापारिक घरानों और उद्योगपति
स्वार्थ संधता है।

इस बात का सबसे अच्छा सबूत हा
होटल ताज पैलेस द्वारा २५० परिवारों को
देना है। होटल में ठहरनेवाले विदेशी पर्यटक
बस्ती को देखकर न भड़कें, इसीलिए उन्हें
दिया गया। फिर एक-दो महीनों तक ये लोग य
वहां दिन काटते रहे और आखिरकार किसी
जगह पर जाकर उन्होंने झुग्गियां डाल लीं।
के बाद से दिल्ली में मात्र दो पुनर्वास कालो
बसायी गयी हैं। शेष उजाड़े गये लोगों को
'ट्रांजिट कैंपों' में डाल दिया गया या उन्हें अपने
पर छोड दिया गया।

ऐसे आफत के मारे लोगों की यही
उभरती है—धूप से झुलसा और पसीने से तर
हड्डियों के ढांचे में जड़ी एक जोड़ी खाली
बिखरे बाल, दाढ़ी-मूंछ और निकोटिनयुक्त
सबमें समान रूप से निहित कुंठा व अज्ञान
अंतहीन व्यथा, भय और बेबसी। उनके लिए
जीवन एक अंधकारमय अस्तित्व है जो निरर्थ
क्योंकि दिल्ली में उनकी हैसियत नाजाय
अवांछित संतान से बेहतर नहीं है।

—राजन

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

सितम्बर प्रथम

नव-वधू विशेषांक

आवरण कथा :

दाम्पत्य : एक सामाजिक समझौता या प्रेम का अनुबंध ?

प्रमुख आकर्षण

- लड़की कैसे दिखाएं ?
- ऐसे प्रश्न, जो नव-वधुएं पूछ नहीं पातीं
- रिश्ता जेठानी-देवरानी का
- क्यों जाते हैं लोग हनीमून पर ?
- विभिन्न जातियों की वैवाहिक रस्में
- मैं डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी
- कैरियर की प्लानिंग में विवाह को न भूलें
- अपने 'उनके' हाथ की रेखाएं पढ़िए
- अब जीजा को नहीं, पति को सराहिए
- सज्जा लंबे बालों की :
नव-वधु के लिए, सखियों के लिए भी
- गहने नयी स्टाइल के

अन्य आकर्षण

- मेरी सुहागरात : मिलन यामिनी : एक सुखद अनुभव
- व्यंजन : 'आज मेरे लिए क्या पका रही हो ?'
- हास्य व्यंग्य : तेरे कूचे से वो निकले/ वसन्त कुमार भट्ट,
आगमन भाग्यलक्ष्मी का/ शांति मेहरोत्रा
- कहानियां : अहसास/ एजाज अहमद,
पोर्ट्रेट/ कुमारश्री मित्र
- फिल्म : कैसी होती हैं फिल्मी सासें ?
साथ ही अन्य सभी स्थाई स्तंभ

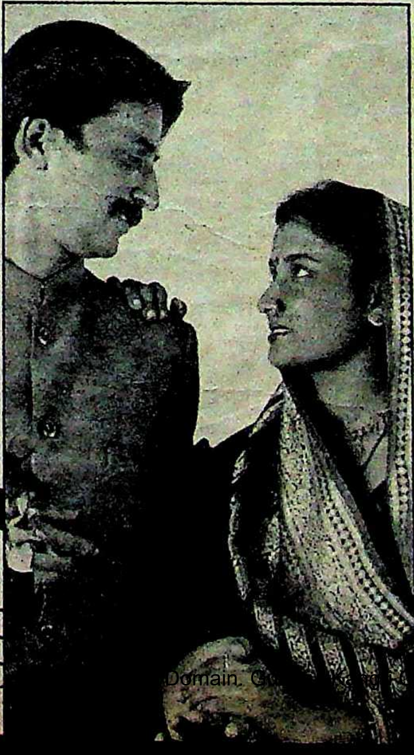

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं !

साक्षात्कार : राजबब्बर

भ्रष्टाचार की जड़ें प्रधानमंत्री के आंगन में हैं

अभिनेता राजबब्बर की शीघ्र प्रदर्शित होनेवाली एक फिल्म 'अंधेरगर्दी' इन दिनों बंबई में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज की स्वार्थी और मतलबी राजनीति और मौजूदा सड़ी-गली व्यवस्था पर चोट करनेवाली इस फिल्म में राजबब्बर ने एक ईमानदार और समर्पित पुलिस इंसपेक्टर की भूमिका निभायी है। समाज के तथाकथित असरदार लोग इस इंसपेक्टर की राह में बार-बार रोड़ा बनते हैं, उसे अपनी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। अपनी असहाय स्थिति के कारण उसके भीतर आक्रोश का लावा उबलने लगता है। कभी-कभी वह स्वयं को पराजित महसूस करता है। वह रोज-रोज का तनाव बरदाश्त नहीं कर पाता और उसका मन घुट रहा होता है, तो वह एक रात शराब का सहारा लेता है। हाथ में बोतल लिये, नशे में धुत इंसपेक्टर अविनाश (राजबब्बर) एक चौराहे पर महात्मा गांधी की एक मूर्ति के सम्मुख खड़ा है। उसकी आंखों में हलके-हलके आंसू तिर आये हैं। वह कभी गांधी को देखता है, कभी जमीन को। कहता है, "क्या हो गया है तेरी कोख को मां? पहले तुम जवाहरलाल और लाल बहादुर पैदा करती थी, आज दलाल पैदा करने लगी हो। इसमें तेरा क्या कुसूर है। तू तो धरती मां है। तेरे लिए तो जवाहरलाल, लाल बहादुर और दलाल, सब तेरे बेटे हैं। चल अविनाश, तू अपनी सोच। यहां तो सब साले अंदर करने में लगे हैं। देश जाये भाड़ में। सब अपनी जेबें भरने में बिजी हैं। यदि इनका बस चले, तो ये अपनी मां की दलाली भी कर दें। (गांधी की ओर देखते हुए) सारी बापू, मेरी आधा पाव शराब तो तुम्हें नजर आ रही है, आज देश में क्या हो रहा है, वह नजर नहीं आता। तुम्हारा नाम, महात्मा गांधी का नाम आज सड़कों का नाम बन कर रह गया है। बड़े-बड़े सरकारी दफ्तरों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें टांग कर रख दी गयी हैं और उन तस्वीरों के नीचे वह सब कुछ हो रहा है, जिसके खिलाफ तुम जीवन भर लड़ते रहे...आज यहां कोई हिंदू है, तो कोई मुसलमान, तो कोई सिख है, तो कोई ईसाई। चिराग लेकर ढूंढ़ने से भी कोई हिंदुस्तानी नहीं मिलता...इधर सारे देश की ऐसी-तैसी हो रही है बापू और तुम ऊपर खड़े होकर देख रहे हो। सारी बापू, आइ लव यू बापू। तुम बहुत अच्छे थे। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी थीं। तुम जानते हो बापू, तुम हार गये। तुम हार गये बापू। हम सब भी हार गये...।"

परदे पर यह लंबा एकालाप कोई दस मिनट तक चलता है। इस एकालाप में जहां राजबब्बर अपनी अभिनय-क्षमता एक बार फिर साबित करते हैं, वहीं उनके मानसिक रुझान का भी पता चलता है।

विद्यार्थी जीवन से अब तक राममनोहर लोहिया के परम भक्त राजबब्बर फिल्मोद्योग के उन चंद कलाकारों में एक हैं जो देश की मौजूदा परिस्थितियों के प्रति जागरूक हैं, सुधरते-बिगड़ते हालात का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और जिनके पास दैनिक अखबार व पत्रिकाएं पढ़ने के लिए वक्त है।

कालेज के वे दिन : बात १९६७-६८ की रही होगी। राजबब्बर 'माया' से कहते हैं, "बड़ा जोश था मुझमें। कुछ कर दिखाने का हौसला था। हां, दोस्त लोग कहते थे कि यार, तू तो हीरो दिखायी देता है, आवाज में भी दम है, फिल्मों में क्यों नहीं जाता? पर उन दिनों दूसरा ही रंग चढ़ा था। समाजवादी युवजन सभा का मैं सक्रिय सदस्य बन गया था। उस समय शायद जनेश्वर मिश्र थे। उन्हीं दिनों वेदप्रकाश वैदिक के नेतृत्व में हिंदी आंदोलन चला था। हम भी उसमें कूद पड़े। खूब नारेबाजियां होती थीं। मीटिंग और सभाएं। छात्र-जीवन में मैंने लोहियाजी को पढ़ा और उनके विचारों का कायल हो गया। वे एकदम ओरिजिनल थिंकर थे। अचानक आगरा पीछे छूट गया। मैंने स्वयं को एक नये परिवेश में पाया। बदला हुआ वातावरण था, नये साथी थे, सभी कलाकार। १९७२ में मैंने नेशनल आफ ड्रामा में दाखिला लिया।"

राजबब्बर कई दूसरे कलाकारों की तुलना में भाग्यशा रहे। उन्हें जल्द की छोटे-मोटे रोल मिलने लगे। उन्हों अपने जीवन का पहला शाट दिया १६ जनवरी, १९७ फिल्म 'शारदा' के लिए। इस फिल्म के निर्माता थे— तलवार और दिग्दर्शक थे, लेख टंडन। अब भी वह दि करके राजबब्बर कहते हैं, "मैं बेहद एक्साइटेड था। छोटा-सा रोल था। मेरा कुल पारिश्रमिक था, ५०० राजबब्बर के गाडफादर साबित हुए निर्माता-निर्देशक चोपड़ा जिन्होंने दिल्ली के स्टेज पर राजबब्बर को दे था। उन दिनों वे अपनी एक बहुत बड़े बजट की फि बर्निंग ट्रेन' के निर्माण में व्यस्त थे। 'दि बर्निंग ट्रेन' ग नहीं पकड़ रही थी, अतः उन्होंने राजबब्बर और जीन अमान के साथ एक छोटी 'क्विकी' के निर्माण का नि लिया। फिल्म थी 'इंसाफ का तराजू' जो अगस्त १९७ शुरू हुई और आनन-फानन पूरी कर ली गयी। १९८ प्रदर्शित यह फिल्म वर्ष की सुपरहिट फिल्म साबित हु तब से अब तक राजबब्बर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं

वीपी सिंह के साथ राजबब्बर छाया:

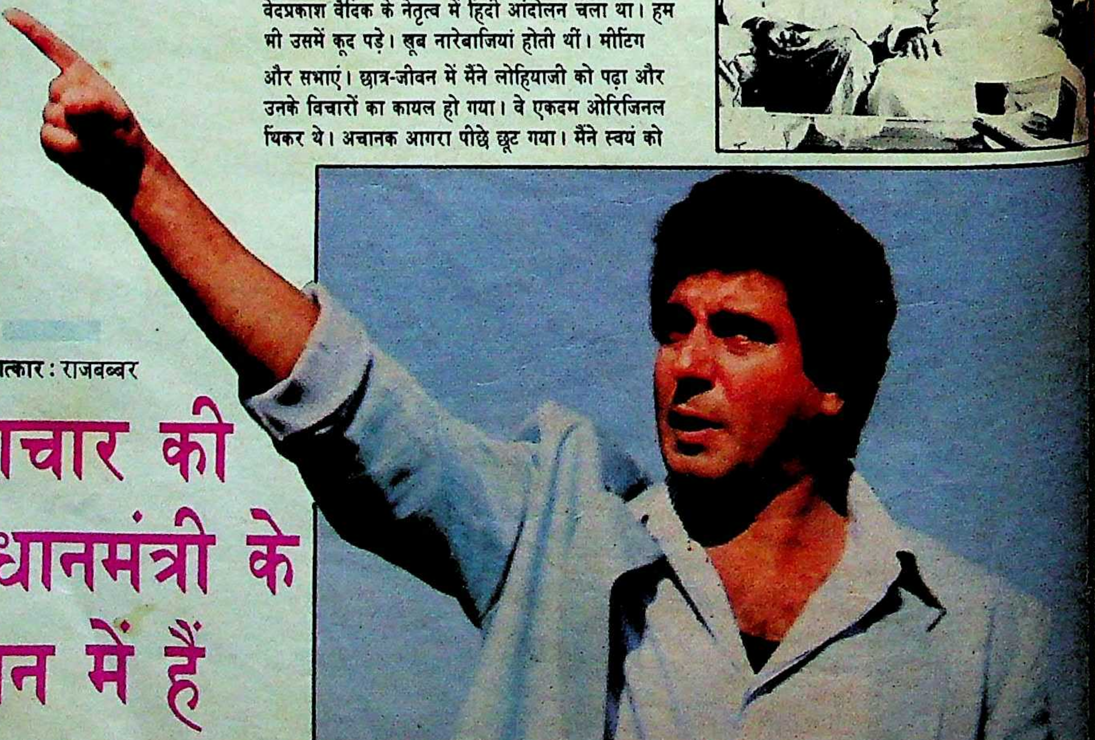

ल्मों के अलावा राजनीति में राजबब्बर की गहरी रुचि । देश के मौजूदा हालात से वे चिंतित हैं और कुछ करना हते हैं, पर सक्रिय राजनीति से बाहर रह कर। रवनाथ प्रताप सिंह की क्षमताओं पर उन्हें गहरा विश्वास । वे दो-टूक शब्दों में कहते हैं, "भ्रष्टाचार की सारी ड़ें प्रधानमंत्री के आंगन में गड़ी हैं।" उनसे 'माया' की हुई तचीत के प्रमुख अंश:

***मा*या: आपके राजनीतिक आधार के बारे में तरह-तरह के विवाद उछलते रहते हैं। भी कुछ दिन पहले खबर आयी थी कि मुरली वड़ा और आपके बीच मुलाकातें हो रही हैं और प कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।**

जबब्बर: (ठहाका लगाते हुए) न जाने कौन है स खबर का सूत्र-बिंदु। मैं शुरू से लोहियाजी का क्त रहा हूं और समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हा। समाजवादी युवजन सभा का सक्रिय सदस्य हा। हां, मैं अब भी किसी राजनीतिक पार्टी का दस्य नहीं हूं, न ही जनता दल का। हां, पैथाइजर जरूर हूं और जनमोर्चा की सभाओं भाग लेता रहता हूं। मैं हमेशा 'वैल्यू-बेस्ड' जनीति का समर्थक रहा हूं न कि चुनावी जनीति का।

या: पर चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति सत्ता तक ले जा सकती है और सत्ता के माध्यम ड़ी जनता के लिए कुछ किया जा सकता है।

जबब्बर: मैं यह नहीं मानता। हर व्यक्ति अपने फेशन के माध्यम से जनता के लिए बहुत कुछ र सकता है। मेरा प्रोफेशन अभिनय है, फिल्म र्माण की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सा लेना है। लाखों रुपए लगाकर अपनी खुद की फिल्म बना ा हूं—'कर्मयोद्धा'। यह फिल्म बुद्धिजीवियों को झकझोर देगी, उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बदलाव की प्रक्रिया तो यह फिल्म भी शुरू कर सकती है। क्या यह मेरा सक्रिय योगदान नहीं हुआ?

माया: क्या है इस फिल्म की थीम?

राजबब्बर: 'डर'। आज हर व्यक्ति में एक 'डर' समा गया है। अमीर भी उतना ही डरता है, जितना एक गरीब। पुलिस भी डरती है और बदमाश भी। एक गुंडे से दूसरे गुंडे का डर है कि न जाने कब पीछे से गोली चल जाये। एक करोड़पति को सरकारी अफसरों का डर है। मैंने इस बार डर की थीम को मुद्दा बनाया है।

माया: पिछले दिनों बंबई में राष्ट्रीय मोर्चा का सम्मेलन हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह मंच पर थे। आप नजर नहीं आये। कोई खास वजह?

राजबब्बर: कोई खास वजह नहीं थी, मैं अपने काम में व्यस्त था, नहीं गया। मैंने आपसे कहा कि मैं जनता दल का सदस्य नहीं हूं। मेरी उनसे सहानुभूति है। मेरा विश्वास है कि मोर्चा में भविष्य के भारत को सही पटरी पर रखने की क्षमता है।

माया: जनता दल के विभिन्न घटकों में फूट है, ऐसा नजर आता है। तब भी आप यह मानते हैं कि जनता दल या राष्ट्रीय मोर्चा भारत की समस्याएं सुलझा पायेगा।

राजबब्बर: हां। मैं अब भी हताश नहीं हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह पर अब भी मुझे पूरा विश्वास है। पिछले दिनों मैं उनसे मिला था। मुझमें रोष था। मैं उबल पड़ा था कि सिंह साहब, यह सब क्या हो रहा है? मेरे दिल की भड़ास को वीपी खामोशी से सुनते रहे। बाद में बोले—'इस देश में कलेक्टिव लीडरशिप की आदत खत्म हो चुकी है। हर पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी हो गयी है। हमारा कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास है—जैसी लीडरशिप स्वतंत्रता-पूर्व के दिनों में थी। एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता। इसके लिए वक्त लगेगा और बदलाव के दिनों में छोटे-मोटे विवाद होते ही रहते हैं। उन्हें मन में मत लाओ। मेरा अब भी इस व्यक्ति (वीपी सिंह) में विश्वास है, क्योंकि उन्होंने सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। वे 'वैल्यू-बेस्ड' राजनीति करते हैं। उनकी सत्ता की राजनीति नहीं है।

माया: क्या आप गंभीरतापूर्वक यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ प्रधानमंत्री हैं?

राजबब्बर: निःसंदेह। वे तमाम भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त हैं। वे हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कुछ यों है कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री में चोरी-छिपे हेरोइन बन रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मालिक है। फैक्ट्री को साफ-सुथरा और निर्दोष रखना उसकी ड्यूटी है। यदि फैक्ट्री में गलत काम हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार मालिक है। आज सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है।

माया: राजनीति से हटकर एक सवाल। फिल्मोद्योग की हालत इन दिनों खस्ता है। बहुतों का यह खयाल है कि आप कलाकार इस अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। दिन-रात पैसा कमाने की हवस ने आप लोगों में अनुशासन नहीं रखा और एक-एक कलाकार ने ३०-३०, ४०-४० फिल्में अनुबंधित कर लीं। फलतः फिल्मों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी। आपका क्या कहना है?

राजबब्बर: आप ठीक कहते हैं। एक्टर नाम की जात भी राजीव गांधी की तरह है। सिर पर चढ़ाओगे, तो जम कर नाचेगा। क्यों फिल्म-निर्माताओं ने एक्टरों को सिर पर चढ़ाया? कुत्तों की तरह क्यों दुम हिलाते रहते हैं? हाथ में हंटर क्यों नहीं रखते कि एक्टर वक्त पर आये और अपने काम को सही अंजाम दे?

—महेंद्र विनायके

र्मयोद्धा' के एक दृश्य में राजबब्बर, डिंपल कपाड़िया और आशालता

जयाप्रदा के साथ 'पराया घर' में राजबब्बर

छाया: मदन चौरसिया

नसीर की परेशानी

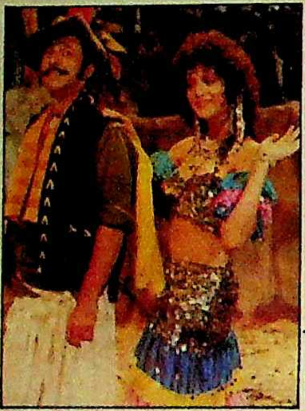
छाया : नरसैया

नसीरुद्दीन शाह और सोनम 'त्रिदेव' में

नसीरुद्दीन शाह के डेढ़ दशक के कैरियर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जैसा 'त्रिदेव' के एक झटकामार (बंबइया भाषा में) 'नृत्य ने कर दिखाया। 'ओए, ओए'...बोल वाले इस नृत्य में जब उन्हें ग्लैमरस सोनम के साथ विशुद्ध बंबइया फिल्मी स्टाइल में नृत्य करने के लिए कहा गया, तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इससे उनकी इमेज बिगड़ जायेगी, लेकिन अंततः काफी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने सोनम के साथ 'कमर मटकाऊ' नृत्य (फिल्मी भाषा में) यह सोचकर करना स्वीकार किया कि दर्शक इस पर ध्यान थोड़े देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। 'त्रिदेव' उसी नृत्य के चलते 'तेजाब' के बाद सर्वाधिक सुपरहिट साबित हुई। लेकिन इस सफलता ने नसीर को परेशानी में डाल दिया है। अब उनके पास ऐसी ही नृत्यवाली भूमिकाओं के ढेर लग गये हैं। उन्हें देखते ही लोग 'ओए-ओए' कह कर चिल्लाने लगते हैं!

नीतू सिंह का पछतावा

बेचारी नीतू सिंह अब पछता रही है कि पता नहीं किन क्षणों में उसने अपने खाविंद ऋषि कपूर और श्रीदेवी के बीच पुनः दोस्ती करा दी थी। हरमेश मल्होत्रा की 'नगीना' तथा 'निगाहें' और यश चोपड़ा की 'चांदनी' के बाद ऋषि ने उन सारी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, जिनमें नायिका श्रीदेवी थी। झगड़े की जड़ थी श्रीदेवी की वह टिप्पणी, जिसमें उसने खुद को ऋषि से बड़ा बतलाया था और 'नगीना' की सफलता का श्रेय खुद अपने पर्स में डाल लिया था। लेकिन इस बीच जब दोनों की फिल्में बाक्स आफिस पर लुढ़कने लगीं, तो उन्होंने दोस्ती की ओर फिर से बढ़ने की जरूरत महसूस की, लेकिन जब यहां भी अहं आड़े आया, तो ऋषि कपूर की पतिभक्त बीवी नीतू अब इसलिए पछता रही है कि हर रोज सही समय पर घर से निकलने तथा घर लौट आनेवाले उसके मियां का सारा समय श्रीदेवी के साथ बीतने लगा है।

श्रीदेवी और ऋषि कपूर फिल्म 'गुरुदेव' में

छाया : आरबी तिवारी

रेखा : मुसीबत का मौसम

लगता है, जुलाई-अगस्त महीने में शनि-राहु-केतु रेखा पर जरूर कुपित हो बैठते हैं और उसे किसी-न-किसी मुसीबत में फंसा देते हैं। १९८६ में उसे इन्हीं महीनों में शनि के प्रतीक आयकर अधिकारियों ने कुछ इस कदर परेशान किया कि मोशाय बाबू से निराश रेखा को राजबब्बर का दामन थामना पड़ा था। मामला तो हल हो गया, लेकिन भाई लोगों ने रेखा-बब्बर के विवाह की खबर उडाकर उसे दूसरी मुसीबत में डाल दिया। १९८७ में एक तथाकथित चोर रेखा के एयरटाइट बंगले में पता नहीं कैसे उसकी छत से भीतर घुस गया था। १९८८ में फिर आयकर अधिकारियों ने तेवर दिखलाये, जिनसे 'ऊपरी पहुंच' के बल पर उसे निजात मिल सकी। अब इसी जुलाई १९८९ में हरदेव सिंह ओजला ने अपने गिरोह के साथ उसे उस समय अपहृत कर २० लाख रुपए फिरौती वसूलने की योजना बनायी, जब वह 'मार्निंग जागिंग' के लिए बैंड स्टैंड पर जाती थी। इत्तफाक से पुलिस को भनक लग गयी, लेकिन बेचारी रेखा अभी भी अपहरण के आतंक के सदमे से नही उबर सकी है।

छाया : नरसैया

ग्रहों का चक्कर : रेखा

आवारा विनी

बेचारी अमृता सिंह उन टे
कालों से आजिज आ गयी
विनी (विनोद खन्ना) का
अबाउट' पूछने के लिए उन
सुबह से ही आने लगते हैं।
कपाड़िया भी ऐसे ही 'काल
इसलिए ज्यादा परेशान है कि
की अधिकांश फिल्मों की
नायिका है। और-तो-और विन
डेट्स कन्फर्म करने के लिए
अकसर अलस्सुबह इनके घर
पहुंच जाते हैं, लेकिन अमृता
लेकर विनोद के सेक्रेटरी तक
नहीं होता कि विनी कब
निकलता है, कहां जाता है और
रह कर वापस लौट आता है।

लेकिन सबसे ज्यादा परे
तो हुई 'लेकिन' के निर्माता हृद
मंगेशकर के इकलौते भाई
निर्देशक गुलजार को, जिन्होंने
को 'मेरे अपने' तथा 'अचान
काम देकर एक नयी इमेज दी
दोनों कार लेकर उन्हें एक ज
दूसरी जगह तलाशते रहे और
डबिंग थियेटर में अकेली बैठी
होती रही।

—अखबारी

छाया : नरसैया

विनोद खन्ना और कपाड़िया

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित

अब नई पैकिंग में

अशोक
मसाले
स्वाद व सुगंध में बेजोड़

स्पेशल मसाले : गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला, जलजीरा, दाल मसाला, रायता मसाला, हाजमी, सांभर मसाला, दम आलू मसाला, चना मसाला, दही बड़ा मसाला, चाट मसाला, चटनी पुदीना, किचन दूत, छोला मसाला, दूध मसाला, मुड़ी मसाला, चाय मसाला, पावभाजी मसाला।

पिसे मसाले : हल्दी, धनियां, मिर्चा, खटाई, जीरा भुना पाउडर, काश्मीरी मिर्च, कालीमिर्च

खड़े मसाले : जीरा, सौंफ मोटी, मेथी, राई, कलौंजी, सौंफ महीन, लाही, अजवाइन, कसूरी मेथी

अन्य : पापड़, हवन सामग्री, बीच साल्ट,

AGMARK
CURRY POWDER
GRADE STANDARD
Ashok
Garam masala
IODIZED
Beach
FREE FLOWING
SALT
Ashok
CHAT
MASALA

अशोक
करी पाउडर
सब्जी मसाला

अशोक
दम आलू
मसाला

अशोक
करी पाउडर
मीट मसाला

PUBLISITES/A M/col/6

उत्तर प्रदेश के बाहर वितरक/स्टाकिस्ट बनने हेतु सम्पर्क करें

मुख्य वितरक

अशोक सेल्स कं. प्रा. लि.
५१/५३, नयागंज - कानपुर २०८००१

सिन्टेक्स

लॉफ्ट टँक्स

आधुनिक रहन-सहन की पहली आवश्यकता

ज़मीन की कमी के कारण एक तरफ़ बहुमंज़िली इमारतें बनाना भी अनिवार्य हो गया है, तो दूसरी तरफ़ पानी की कमी की समस्या पैदा हो गई है. और इस पर यदि आपकी इमारत में रहने वाले हर घर-परिवार के लिए एक ही पानी की टंकी लगी हुयी है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके नल में पानी आएगा भी या नहीं? ख़ास तौर पर उस समय, जब आपको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.

सिन्टेक्स —वक़्त की कसौटी पर अव्वल, एकमात्र लॉफ़्ट टंकियां.

सिन्टेक्स लॉफ़्ट टंकियां आपके बाथरूम या टॉयलेट या फिर रसोई-घर के ऊपर बनी छोटी सी संकरी अटारी (लॉफ़्ट) पर पानी संग्रह करने के लिए ख़ास तौर से बनायी गयी है, ताकि आपको चौबीस घंटे लगातार पानी मिल सके... यानी एक ऐसी सुविधा और आराम जो आज के आधुनिक रहन-सहन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है.

बरसों से भारत के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवार इन टंकियों को घरों में लगाते आ रहे हैं. और अपने घरों एवं दफ़्तरों में लगातार २४ घंटे पानी की सुविधा का लाभ उठाते आ रहे हैं. यह सबूत है हर सिन्टेक्स लॉफ्ट् टंकी की उत्कृष्ट क्वालिटी और भरोसेमंद उत्तम सेवा का.

सिन्टेक्स -बेजोड़ फायदे

★ इस्तेमाल के लिए तैयार, लगाने में आसान ★वज़न में.हलकी और सुगठित ★पैसे और बहुमूल्य जगह की बचत कराए ★देखभाल से १०० %मुक्त ★१०० %आरोग्यकर ★५०० लिटर तक की विविध क्षमताओं में उपलब्ध ★साथ ही दीवार पर लगाने के लिए सम्पूर्ण साजो-सामान (वॉल माउंटिंग किट) सहित उपलब्ध.

अधिक जानकारी के लिये यहां संपर्क करें:

सिन्टर प्लास्ट कन्टेनर्स
प्लास्टिक्स डिव्हिजन द भारत विजय मिल्स लि. कलोल (उ. गुजरात) ३८२ ७२१
फोन: (०२७६४), २२२८, ३१४४, ३१४५ ग्राम: "SINTEX"
टेलेक्स: ०१२०५/२०२ SPC IN फॅक्स: (०२७६४) २४३६

सिन्टेक्स दुनिया की नं. १ प्लास्टिक टंकियां

Digitized by Arya Samaj Foundation C... eGangotri

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक १९
१५ अक्टूबर, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५, लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७, पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५, जयपुर कार्यालय: ए-२०, शांति पथ, तिलकनगर, जयपुर-४, फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के
सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

श्री वीरेंद्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित

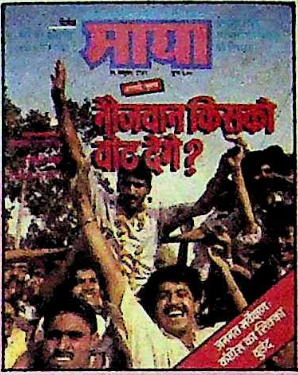

२४
आवरण कथा

नौवीं लोकसभा के लिए होनेवाले आमचुनाव में १८ से २० वर्ष के नवमताधिकार प्राप्त छह करोड़ युवाओं के साथ २१ से २५ वर्ष के नौ करोड़ युवा भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर संसदीय क्षेत्र में औसतन एक तिहाई संख्या में विद्यमान यह नौजवान-शक्ति किसे वोट देने का मन बना रही है? 'माया' ने इसकी पूरी तहकीकात की है। शहरी युवाओं के मानस का पता लगाने का उत्तरदायित्व सर्वेक्षण संस्था आईएमआरबी को सौंपा गया, तो ग्रामीण युवाओं के मन की थाह पाने का कार्य 'माया' टीम ने खुद किया। प्रस्तुत है, सर्वेक्षण-रिपोर्टों के साथ देश की युवा-शक्ति के हालात और मानसिकता का विश्लेषण:

नेपाल
नेपाल सरकार द्वारा भारत को आंखें दिखाने से आम नेपालियों को किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है? **७०**

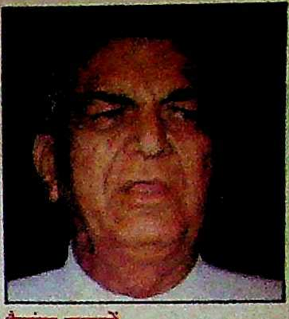

गैरइंका सरकारें
विपक्षी नेताओं को यह आशंका क्यों है कि कांग्रेस गैरइंका सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है? **८७**

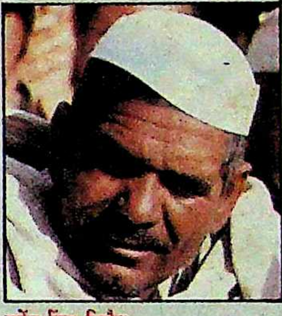

महेंद्र सिंह टिकैत
टिकैत-तिवारी समझौते के बाद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का झुकाव कांग्रेस की ओर हो गया है? **६०**

फिल्म
बड़े बजट की फिल्मों के पिटने से संकट में पड़े फिल्म उद्योग को क्या कलात्मक फिल्में बचा सकती हैं? **८१**

बिहार
रामलखन यादव के कांग्रेस से खफा होने के कारण क्या बिहार में यादव-वोट भी कांग्रेस-विरोधी हो जायेंगे? **४२**

क्रिस एवर्ट
दुनिया की चोटी की टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट ने संन्यास लेने से पहले क्या कीर्तिमान स्थापित किये? **९४**

दिल्ली दरबार: तिवारीजी स्थिर रहेंगे! १०
फोटो फीचर १३
बकौल लिमये: राजनीति का अपराधीकरण: माफिया युग की दस्तक १७
अर्थतंत्र: सिंहानिया घराना और सरकार २०
आवरण कथा: जनमत सर्वेक्षण के खतरे ३४
आवरण कथा: युवा मतदाता की मानसिकता ३८
राजस्थान: बेलगाम पुलिस ४७
समाज: जानलेवा उपेक्षा ५६
मध्य प्रदेश: आधा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ पटवा का मोर्चा ६५
दूरदर्शन: पंछी: परदेशियों का दर्द ६८

आवरण पारदर्शी
एस पाल

maxell LN 90
TDK
तुलसी
तुलसी जर्दा
00
तुलसी
जर्दा
ZARDA

सर्वश्रेष्ठ...
सर्वोत्तम...
सर्वप्रथम... ज़र्दा पाउच में
तुलसी ज़र्दा

- सुविधाजनक आकार
- सुविधाजनक कीमत
- असली ताज़ा ज़र्दे का भरोसा... हर बार !

शानो शौकत के ढंग... तुलसी ज़र्दा के संग

अनेकानेक वैरायटीज़ में उपलब्ध
धर्मपाल सत्यपाल

हत्या क
अब पर

३० सित
आ
साजिश
अगस्त,
एक विमा
ने अनुमा
दुर्घटना मे
निगाहें
लगी थीं
तह में ज
आखिर स
तय हो
सामान पू
था, वह
इतिहास
की ऐसी
लिए वेटे
फिर जिय
तो देर-स
हसन, मि

मैं जनत

'माया'
प्रक
मिन्हा के
लगे। रा
फिल्म इं
अभिनेता
गलत नी
आवाज
सच्चे जा
होने का
अग्रवाल
उम्र

माया
जिया की पहली बरसी
हत्या की साजिश का अब परदाफाश

हत्या की साजिश का अब परदाफाश

३० सितंबर की 'माया' मिली। आवरण कथा 'जिया की हत्या की साजिश का परदाफाश' पढ़ी। १७ अगस्त, १९८८ को जब जिया की मौत एक विमान हादसे में हुई थी, तब लोगों ने अनुमान लगाया था कि उनकी मौत दुर्घटना में हुई है। लेकिन संसार भर की निगाहें उसकी असलियत जानने पर लगी थीं और खुफिया एजेंसियां उसकी तह में जाने की कोशिश कर रही थीं। आखिर साल भर के प्रयास के बाद यह तय हो ही गया कि उनकी मौत का सामान पूर्वनियोजित ढंग से जुटाया गया था, वह भी उन्हीं की सेना द्वारा। खैर इतिहास गवाह है कि मुसलमानों में सत्ता की ऐसी भूख रही है कि सत्तासीन होने के लिए बेटे ने अपने बाप को नहीं बख्शा है, फिर जिया जैसे निरंकुश शासक के साथ तो देर-सवेर यह होना ही था।—**नज्मुल हसन, भिमंडी, बंबई**

मैं जनता का आदमी हूं

'माया' (१५ सितंबर, १९८९) में प्रकाशित फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के विचार बेहद सटीक व सार्थक लगे। राज बब्बर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे ऐसे जागरूक अभिनेता हैं जिसने राजीव सरकार की गलत नीतियों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर राष्ट्र के प्रति एक सच्चे जागरूक और देशभक्त नागरिक होने का परिचय दिया है।—**मुकेश अग्रवाल 'मुकेश', सावन कटरा, आगरा, उप्र**

मुसलमान किसको वोट देंगे ?

१५ सितंबर की आवरण कथा 'मुसलमान किसको वोट देंगे ?' पर हमारे पास ढेर सारे पत्र आये हैं। स्थानाभाव के कारण हम सभी पत्रों को स्थान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कुछ चुनिदा पत्रों को जस-का-तस छाप रहे हैं :

__बस्ती से शोएब रहमान__ 'माया' पर रीझते हुए लिखते हैं : "आम तौर पर मुझे 'माया' में कोई रुचि नहीं, परंतु इस बार 'माया' देखते ही लालच-सी लगी और तुरंत खरीद लिया ! 'मुसलमान किसे वोट देंगे ?' इस शीर्षक के साथ अपने लेख में आपने आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो तस्वीर खींची है, वही हकीकत है। आपने तो उर्दू प्रेसवालों को शर्मसार कर दिया जो आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पेश कर सके। 'माया' को जितनी भी बधाई दी जाये, कम है।"

जहां रहमान साहब ललचा गये, वहीं __सतना से दादूराम सलोने चौकन्ना__ का विचार है : "फिलहाल अल्पसंख्यक वोटरों के इस वर्ग का बृहद समर्थन कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा रहने की संभावना है। अयोध्या जन्म भूमि विवाद के चलते मुट्ठीभर कठमुल्ला मुसलमान, विपक्ष के वोटर बन सकते हैं, किंतु सच्चे अर्थों में देश के प्रति समर्पित मुसलमान भाई फिलहाल कांग्रेस को ही समर्थन देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जितना अधिक काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है, उतना काम विरोधी दल सत्ता में आने के बाद नहीं कर पायेगा।"

लेकिन __इटावा__ के __राजीव वर्मा__ मुसलमान भाइयों को सलाह देते हुए कहते हैं : "मैं तो मुस्लिम भाइयों से यही कहूंगा कि वे चुनाव में धार्मिक भावना को आड़े न आने दें, क्योंकि यदि धार्मिक भावना में आकर उन्होंने ऐसी सरकार चुन ली जो उसे सिर्फ भ्रष्टाचार, महंगाई, गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी जैसे तौफे दे, तो एक बार फिर मुस्लिम भाइयों को ५ वर्ष के लिए पिसना पड़ेगा।"

__सहरसा से निर्मल कुमार आया__ लिखते हैं : "मैं 'माया' का नियमित पाठक हूं। १५ सितंबर के अंक में कुमारेश चक्रवर्ती का आलेख 'मुस्लिम मतों का महत्व' पढ़ा। उसमें उन्होंने जरूरत से ज्यादा भावुक होकर मुस्लिमों के प्रति लिखा है। वहीं __गया से अनदलीब अख्तर__ 'माया' के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखते हैं : "इससे पहले मैंने किसी हिंदी पत्रिका में इतने विस्तार और सचाई से मुसलमानों पर लेख नहीं पढ़ा था। अल्लाह से दुआ करता हूं कि इन लेखकों की कलम में और ताकत दे, ताकि इसी तरह वे 'माया' के पन्नों की रौनक बढ़ाते रहें।"

कथा में हुए विश्लेषण से प्रभावित होकर __ग्वालियर से मोहम्मद सलीम__ लिखते हैं : 'माया' ने मुस्लिम मतों का जो विश्लेषण किया है, तथा मुस्लिम मतदाता क्या फैसला लेंगे ? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय राष्ट्र की एकता, अखंडता और देश में फिरकापरस्त, सांप्रदायिक और विघटनकारी शक्तियों के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान की बागडोर सौंपना चाहेंगे जो धर्म निरपेक्ष होने के साथ ही उनके हितों के लिए सोचे।"

यही आवरण कथा पढ़कर __भोपाल__ के __राजेश श्रीवास्तव__ शहाबुद्दीन साहब से सवाल करते हैं : "शहाबुद्दीन ने स्वयं को मुल्क से प्यार करने वाला और राष्ट्रवादी सिद्ध किया है। क्या चुनाव निकट हैं इसलिए ? यह वही राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने भारत माता को चुड़ैल और डायन की संज्ञा दी थी और सोचा था कि मैं मुसलमानों का नेता बन जाऊंगा, पर जब हमारे राष्ट्र के मुसलमानों ने इनके पीछे चलने में रुचि नहीं दिखायी, तो इन्होंने सांप्रदायिक जहर उगला और अपने घिनौने चेहरे को छुपाने के लिए राष्ट्रवादिता का नकाब ओढ़ लिया। कितने मुखौटे बदलोगे नेताजी ?"

जिस तरह के सवाल राजेश श्रीवास्तव ने शहाबुद्दीन से किये हैं, लगभग उसी प्रकार के सवाल __गया__ के __शब्बर नकवी__ गुलाम नबी आजाद से करते हैं : "क्या आजाद यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने सारे कब्रगाह किसने बनवाये जैसे—मेरठ, अहमदाबाद, मलियाना, जयपुर, बड़ौदा, बिहार शरीफ, हापुड़, मुरादाबाद, जमशेदपुर। क्या ये सभी वीपी सिंह ने बनवाये या फिर आजाद के चहेते प्रधानमंत्री ने बनवाये और या फिर प्रधानमंत्री के चहेते मुख्यमंत्रियों ने बनवाये ? यह सब कांग्रेस-इ के ही राज्य में हुआ है।"

काली के कांग्रेस में आने का मतलब

१५ सितंबर की 'माया' में विकास कुमार झा की सामयिक रपट 'काली के कांग्रेस में आने का मतलब' सटीक लगी। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित बिहार के इकलौते निर्दलीय सांसद काली प्रसाद पाण्डेय की कांग्रेस में वापसी से गोपालगंज में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित हो गयी है।—**दीपक कुमार दीक्षित, छज्जूबाग, पटना, बिहार**

टिकैत ने सरकार के फिर घुटने टिकाये

१५ सितंबर की 'माया' में 'टिकैत ने सरकार के फिर घुटने टिकाये' में भारतीय किसान यूनियन के भोपा में दिये धरने के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। इसे पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि आज गरीब की कहीं भी सुनवाई नहीं है, चाहे वह नईमा जैसी भली लड़की की जान का ही क्यों न प्रश्न हो ? यदि पहले ही पुलिस मुस्तैदी से काम लेती, तो यह बिन बुलायी मुसीबत न आती।—**दीपक मलिक, गांधी कालोनी, मुजफ्फरनगर**

महर्षि मनु अदालत में

'माया' के १५ सितंबर, १९८९ अंक में 'महर्षि मनु अदालत में ?' पढ़ा। पढ़कर गहरा सदमा लगा। जयपुर उच्च न्यायालय परिसर में जो नाटक हुआ, उसके पीछे आरक्षण की अफीम चखे चंद सुविधाभोगी लोग हैं। न्याय के मंदिर को विभिन्न जातीय गुटों में विभाजित करने में वे कामयाब हो गये। महर्षि मनु की मूर्ति हो या महर्षि वाल्मीकि या युग पुरुष अंबेदकर की, उससे उन्हें कुछ नहीं लेना-देना। —**गोपालजी सहाय, टाइप ए/१०३, बरौनी, उर्वरकनगर, बिहार**

कांग्रेस में बगावत

१५ सितंबर की 'माया' मिली। विपक्ष और खासकर वीपी सिंह की यह उम्मीद कि कांग्रेस में बगावत होगी, पूरी तरह गलत लगती है, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह और नांजे गौड़ा के बाद कांग्रेस से किसी नेता ने नाता नहीं तोड़ा, बल्कि विपक्ष के ही नेता कांग्रेस में आ रहे हैं।—**राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, दामोदर कालोनी (पश्चिम पल्ली), पो०-अण्डाल, जि०—बर्दवान, पश्चिम बंगाल**

गद्दार बेरोकटोक घूम रहे हैं और संसद में घुसने में भी कामयाब हो गये हैं।**—राजीव गांधी**

जो बात अपने बारे में कहनी होती है, उसे राजीवजी प्रायः दूसरों के बारे में कह जाते हैं**—कमलापति त्रिपाठी**

राजीव गांधी इस हद तक बौड़म हैं कि अपनी अयोग्यता और अक्षमता का भी इजहार कर जाते हैं।**—जद नेता जार्ज फर्नांडीस**

यह (हरियाणा सरकार) एक परिवार के लिए, एक परिवार द्वारा बनायी गयी एक परिवार की सरकार है।**—गुलाम नबी आजाद**

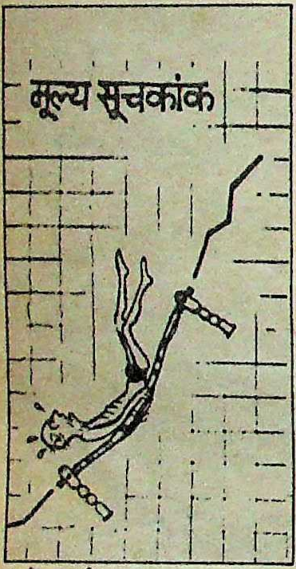

कार्टून : सुशील कालरा

मैं चकित हूं कि षष्ठिपूर्ति कर चुके बुजुर्गों को मिलनेवाला यह दुर्लभ सम्मान (ज्ञानपीठ पुरस्कार) मुझे कैसे मिल रहा है?**—तेलुगू साहित्यकार डा० सी० नारायण रेड्डी**

हमारा पहला काम कांग्रेस-इ को हराना है, नया प्रधानमंत्री तलाशना नहीं।**—ज्योति बसु**

अब देशवासी राजीव गांधी को सेवामुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।**—पी उपेंद्र**

न तख्त है, न ताज है
गीदड़ों का राज है।**—भाजपा का (भारत बंद पर) नारा**

जो पार्टी, जो सरकार अपराधियों और माफियाओं के ही बल पर चल रही हो, उससे आप आशा ही क्यों करते हैं कि वह न्याय दिलायेगी? **—रामविलास पासवान**

दूरदर्शन अपहृत हो चुका है, आधे से अधिक देशवासियों के विचारों और आकांक्षाओं को नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है।**—राजमोहन गांधी**

मैं बारंबार कहूंगा कि राजीव गांधी ने इंका-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का स्तर चपरासी जैसा बना दिया है।**—भाजपा विधायक बाबूलाल गौर**

ज्योति बसु को राष्ट्रपति ने नियुक्त नहीं किया है, न वे उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक तरीके से ही हटाया जा सकता है।**—एबीए गनी खां चौधरी**

गनी खां चौधरी बंगाल कांग्रेस-इ के विभीषण हैं, उन्हें हम न अपना नेता मानते हैं, न उनकी बात मानेंगे।**—सुब्रत मुखर्जी, इंटक अध्यक्ष तथा इंका विधायक**

प्रदेश (उप्र) में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला होने से नारायण दत्त तिवारी पर कोई विशेष अभियोग नही बनता, ये (अपराध, भ्रष्टाचार) तो कांग्रेस संस्कृति के स्थायी भाव हैं।

× × ×

पुरुष के भाग्य और नारी के चरित्र को तो जाना जा सकता है, पर कांग्रेसी राजनीति को नहीं।**—'नवभारत टाइम्स'**

मेरा पहला प्यार तो जनता दल से ही है, मगर जब मेरी माशूका एक खलनायक (भाजपा) की ओर आंखें मटका रही है, तो मैं क्या करूं?**—सैयद शहाबुद्दीन 'संडे'**

कश्मीर राजीव का तुरुप का पत्ता है, वे हिंदुओं से कहेंगे, "मुझे वोट दो, क्योंकि मैंने कश्मीर को हिंदुस्तान में बनाये रखा है।"**—जीएम शाह, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री**

इंग्लैंड सिर्फ शराब के नशे में धुत रहनेवाला देश नहीं, बल्कि एक अश्लील और भद्दा देश भी है।**—अंथोनी बर्गेस, अंग्रेजी का उपन्यासकार**

गदर तो अपने आप होगा।**— एनटी रामाराव**

टिकैत (किसान नेता) को महात्मा कहना राई को पर्वत करार देना है।**—अजीत सिंह, जद महासचिव, 'टाइम्स आफ इंडिया'**

वीपी सिंह का संपूर्ण राजनीतिक इतिहास चुनौतियों से पलायन का इतिहास है। यदि पलायन के लिए कोई ओलंपिक पुरस्कार है, तो वीपी सिंह को स्वर्णपदक मिलना चाहिए।**—इंका सांसद वीएन गाडगिल**

जो व्यक्ति (वीपी सिंह) जनता के हित में सर्वोच्च पद तक त्यागने का माद्दा रखता है, वही प्रधानमंत्री पद के लिए सही आदमी है।**—देवीलाल**

मेरा पक्का विश्वास है कि ज्योति बसु यदि सत्ता से हटे, तो पहली उड़ान से ही लंदन चले जायेंगे।**—प्रियरंजन दास मुंशी**

राजनीति करनेवाले सबके-सब 'लिंपेट (घोंघे) होते हैं।**— चो रामस्वामी, 'स्टेट्समैन'**

अब अगर हम एक संसद सदस्य की जगह एक बैल को दिल्ली भेजें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?**—सुभाष घीसिंग, 'द वीक'**

अगर अब हम चूकेंगे, तो अपराधियों द्वारा अपराधियों के हितार्थ अपराधियों की सरकार बनायी जाने में देर नहीं लगेगी।**—न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर**

मैं उतना ही आत्म-सम्मान चाहनेवाला व्यक्ति हूं जितने राजीव गांधी या वीपी सिंह।**—हाजी मस्तान, 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया'**

हमने कात्रे (सीबीआई प्रमुख) को एक तंदुरुस्त बच्चा (नस्ली वाडिया की हत्या के प्रयास का प्रकरण) दिया है, वे शायद उसे भूखा रखकर मार डालेंगे।**—बंबई पुलिस, 'संडे'**

मैंने शब्दकोश देखकर पुष्टि कर ली है, 'डार्लिंग' असंसदीय लफ्ज नहीं है।**—नजमा हेपतुल्ला**

तवे की रोटी (राजनीतिक सत्ता) काफी जल चुकी है, अब इसे पलटना ही होगा।**—राज बब्बर**

रोज सबेरे जब वे (पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर) दाढ़ी बनाते समय अपनी शक्ल निहारेंगे, तब उन्हें सचाई का पता चल जायेगा जिसे वे नकार नहीं सकते।**—जनरल के सुंदरजी, 'इंडिया टुडे'**

जनरल सुंदरजी के साक्षात्कार से फूटे सत्य को सरकार क्या कहेगी? क्या सेना का जनरल भी झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री महोदय? **—लाल कृष्ण आडवाणी**

शायद जनरल सुंदरजी यह उम्मीद किये बैठे थे कि (अवकाश ग्रहण के बाद) राज्यपाल या राजदूत बना दिये जायेंगे।**—जे वेंगलराव**

संभव है, जनरल वैद्य की हत्या इसलिए की गयी हो, क्योंकि वे खूब जानते थे कि हथियारों की विदेशी आपूर्ति में किन लोगों ने दलाली खायी है।**—एनटी रामाराव**

ज्योति बसु

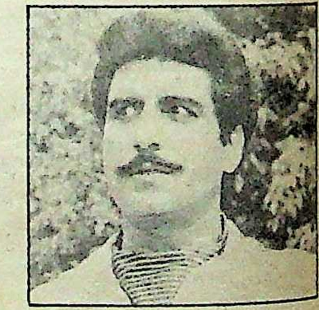

राज बब्बर

सच तो यह है कि मैं कभी सेंट किट्स गया ही नहीं, जबकि अखबारों ने फर्जी दस्तावेज छाप कर मुझे सेंट किट्स की राजधानी बासटेरे में दस्तखत करते दिखाया है।**—अजय सिंह, वीपी सिंह के पुत्र**

मेरे शौहर चाहते हैं कि हमारे पांच बच्चे हों, मगर मैं काफी उम्रदराज हूं और दो से ही खुश हूं।**—बेनजीर भुट्टो, 'फ्रंटलाइन'**

दोनों महाशक्तियों की आकांक्षाएं लुप्त हो गयी हैं और भारत की (आकांक्षाएं) बढ़ गयी हैं, रिक्तता को भरने के लिए।**—'द इंडिपेंडेंट', लंदन**

यह पक्की बात है कि अमिताभ बच्चन राजनीति के लिए (समाज और अभिनय क्षेत्र से) नहीं कटे हैं, वे सिर्फ कट जाने के लिए कट गये हैं।**—शत्रुघ्न सिन्हा**

महोदय?
ह उम्मीद
ग्रहण के
दूत बना
ाव
की हत्या
कि वे खूब
ी विदेशी
दलाली
राव
ंट किट्स
खबारों ने
मुझे सेंट
ासटेरे में

।—अजय

क हमारे
मैं काफी
ही खुश
लाइन
ाकांक्षाएं
ारत की
रिक्तता
डिपेंडेंट,

अमिताभ
(समाज
ही कटे हैं,
कट गये

विश्व-प्रसिद्ध श्रृंखला

जनरुचि के 50 लघु विश्वकोशों (*MINI—ENCYCLOPEDIAS*)
की एक अनूठी संग्रहणीय श्रृंखला।

खोजें
अनसुलझे रहस्य
रोमांचक कारनामे
युद्ध
101 व्यक्तित्व
धर्म मत एवं सम्प्रदाय
खेल और खिलाड़ी
रिकार्ड्स
वैज्ञानिक
विनाश-लीलाएं
दुर्घटनाएं
गुप्तचर संस्थाएं
जासूस
प्रेरक प्रसंग
बैंक डकैतियां
जासूसी कांड
हत्यारे
सभ्यताएं
रोमांस कथाएं
खजाने
दुस्साहसिक खोज-यात्राएं
जन-क्रांतियां
भूत-प्रेत घटनाएं

श्रृंखला के नये मोती

कुख्यात महिलाएं
विलासी सुंदरियां
राजनैतिक हत्याएं
हस्तियों के प्रेम-प्रसंग
तख्तापलट की घटनाएं
सनकी तानाशाह

इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है।

उदाहरणार्थ **रोमांचक कारनामे** में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो **खोजें** में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। **अनसुलझे रहस्य** में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो **खेल और खिलाड़ी, 101 व्यक्तित्व** व **वैज्ञानिक** जीवनी-प्रधान पुस्तकें हैं। **विनाश-लीलाएं** व **दुर्घटनाएं** में मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है तो **गुप्तचर संस्थाएं, जासूस** व **जासूसी कांड** में जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं। **सभ्यताएं** और **प्रेरक-प्रसंग** किसी भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो **हत्यारे** में रक्त-पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। **रोमांस-कथाएं** तथा **हस्तियों के प्रेम-प्रसंग** में लैला-मजनूं से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन, नेहरू जैसे व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं तो **अनमोल खजाने** में रहस्य और रोमांच से भरे खजाने हैं। **दुस्साहसिक खोज-यात्राएं** में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं तो **जन-क्रांतियां** में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का सिलसिलेवार ब्यौरा है। **भूत-प्रेत घटनाएं** पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी। **कुख्यात महिलाएं** तथा **विलासी सुंदरियां** में मर्लिन मुनरो, जैक्लीन कैनेडी जैसी औरतों के निजी जीवन में झांकने की कोशिश की गयी है तो **राजनैतिक हत्याएं** तथा **तख्ता-पलट घटनाएं** में आपको विश्व-कूटनीति का असली चेहरा दिखायी देगा।

कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने वाला एक सचित्र **मिनि एनसाइक्लोपीडिया** है।

मूल्य: 18/- प्रत्येक
डाकखर्च: 4/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें
मंगाने पर डाकखर्च माफ

■ प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री ■ प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित ■ सरस कथा शैली ■ फोटोटाइप सैट ■ बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई ■ बहुरंगी आवरण ■ वाजिब दाम

अपने निकट व ए. एच. व्हीलर के रेलवे व बस अड्डों के बुकस्टॉलों पर मांगें। वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के पते :-

पुस्तक महल खारी बावली, दिल्ली-110006
शोरूम: 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.

देश

१ सितंबर : आंध्र प्रदेश के करीम नगर में नक्सलियों द्वारा एक जीप उडाये जाने से ११ व्यक्तियों की मौत। आठ सदस्यीय चयन समिति द्वारा १९८८ के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार हेतु पीएलओ नेता यासिर अराफात का चयन।

२ सितंबर : रूपा गांगुली को धारावाहिक 'महाभारत' में द्रौपदी की अच्छी भूमिका निभाने के लिए १९८९ का स्मिता पाटिल पुरस्कार।

३ सितंबर : आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार, ५ नये मंत्री शामिल। आंध्र प्रदेश प्रजापरिषद के अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी अपहरणकर्ताओं द्वारा रिहा।

४ सितंबर : भारतीय शांति सेना के ७०० जवान श्रीलंका से स्वदेश वापस। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड मसले पर त्रिपक्षीय समिति की बैठक का बहिष्कार। त्रिपुरा मंत्रिमंडल में फेरबदल।

५ सितंबर : शिक्षक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा २६८ शिक्षक पुरस्कृत।

६ सितंबर : बिहार में आठ लाख गैरराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज ठप। उड़ीसा विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य में बिगडती कानून-व्यवस्था पर बहस की मांग को लेकर हंगामा।

७ सितंबर : ५८ वर्षीय कांग्रेस-इ सांसद चंद्रा त्रिपाठी का निधन। शशिकांत परमार उर्फ माली को राजकोट जिला जेल में फासी। महेंद्र सिह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता।

८ सितंबर : नगालैंड मंत्रिमंडल का विस्तार, छह नये मंत्री शामिल। शांति सेना के मसले पर भारत-श्रीलंका के बीच समझौता।

९ सितंबर : राष्ट्रीय संजय मंच के पूर्व नेता अकबर अहमद डंपी जनता दल से निष्कासित। अंजू सचदेव दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित।

१० सितंबर : मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का ३९ दिन पुराना भोपा आंदोलन समाप्त। जनता दल से निष्कासित अकबर अहमद डंपी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र। सैयद अली अशर्फी उत्तर प्रदेश जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त।

११ सितंबर : देवीलाल से इस्तीफे की मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा के समक्ष धरना देने जा रहे तीन हजार कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार।

१२ सितंबर : कांग्रेस-इ के सभी सदस्यों द्वारा पश्चिमी बंगाल विधानसभा का बहिष्कार।

१३ सितंबर : सेंट कीट्स में खाता संबंधी विवाद को हल करने के लिए जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह के पुत्र अजय सिंह द्वारा सरकार से मुकदमा चलाने की पेशकश। १९८९ के जमना लाल बजाज पुरस्कार से इटली के डैनिलो डोलसी, भारत के के० जनार्दन पिल्लई, टीजी मेनन तथा श्रीमती इंदिरा बाई लहबे सम्मानित।

१४ सितंबर : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा छह प्रमुख खिलाड़ियों के खेलने पर लगायी गयी एक साल की पाबंदी समाप्त।

१५ सितंबर : १९८८ का ज्ञानपीठ पुरस्कार तेलुगू साहित्यकार डा० सी० नारायण रेड्डी को देने की घोषणा। राजीव गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में न्यूजप्रिंट प्लांट और बदायूं में खाद कारखाने का शिलान्यास।

यासिर अराफात

डा० शंकर दयाल शर्मा

फिदेल कास्त्रो

रणसिंघे प्रेमदास

विदेश

१ सितंबर : गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक बेलग्रेड में शुरू। क्यूबा के पूर्व आंतरिक मंत्री जनरल अब्रान्तेस को सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में २० वर्ष की सजा।

२ सितंबर : सिंगापुर के राष्ट्रपति वी किम वी आगामी चार वर्षों के लिए पुन: राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को दस करोड़ पौंड की मदद देने का फैसला। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस और जातिवाद विरोधी प्रदर्शनकारियो के बीच झड़पों में ४०० लोग गिरफ्तार।

३ सितंबर : बांग्लादेश में देशव्यापी हड़ताल, तीन लोग मरे, १०० घायल। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो द्वारा नौवें निर्गुट शिखर सम्मेलन में भाग न लेने की घोषणा। जापान में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे ३१ चीनी गिरफ्तार।

४ सितंबर : नवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में प्रारंभ। क्यूबा में विमान दुर्घटना में १२६ लोग मरे। लोकतंत्र समर्थक चीन के सांस्कृतिक मंत्री वांग मंग अपदस्थ।

५ सितंबर : अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की सभा में बेन जानसन द्वारा बनाये गये विश्व रिकार्ड को रद्द करने का फैसला। ब्रिटेन और भारत के बीच समझौता, ब्रिटेन द्वारा भारत को २.७९ करोड़ डालर का अनुदान।

६ सितंबर : श्रीलंका में सिंहली उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण।

७ सितंबर : दक्षिण अफ्रीका में सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी को पुन: बहुमत।

८ सितंबर : आर्मीनिया में भूकंप का तेज झटका। पश्चिमी डेनमार्क में नार्वे का एक विमान ५२ यात्रियों सहित समुद्र में गिरा।

९ सितंबर : राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास देश में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए विपक्ष की मांगों पर विचार करने के लिए सहमत। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और आदिवासी छापामारों के बीच गोलाबारी में दो सुरक्षाकर्मियों सहित तीन व्यक्ति मरे।

१० सितंबर : नेपाल सरकार के खिलाफ 'जन जागरण कार्यक्रम' चलाने के तहत नेपाल कांग्रेस के १४०० लोग गिरफ्तार। रोमानिया का एक जहाज डेन्यूब नदी में डूबने से १६४ लोग लापता। पश्चिम जर्मनी की स्टेफीग्राफ ने अमरीका की मार्तिना नवरातिलोवा को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीता।

११ सितंबर : श्रीलंका में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा विश्वविद्यालय के एक कुलपति सहित ३१ व्यक्तियों की हत्या।

१२ सितंबर : पोलैंड की संसद द्वारा सालिडेरिटी सरकार के गठन को सर्वसम्मति से स्वीकृति। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जूनियस जयवर्धने की भाभी ग्लैडिस जयवर्धने की जनता विमुक्ति पेरामुना के आतंकवादियों द्वारा हत्या। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी जनसंगठन (स्वापो) के श्वेत पदाधिकारी एण्टन लुबोस्की की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हत्या।

१३ सितंबर : ब्रिटेन में इस्लामी पार्टी का गठन। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास देश में शांति बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार।

१४ सितंबर : दक्षिण अफ्रीका में सत्तारूढ़ गोरों की नेशनल पार्टी के नेता एफडब्ल्यूडी क्लर्क सर्वसम्मति से पांच सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित।

१५ सितंबर : पाकिस्तान को कामन व्हेल्थ की सदस्यता पुन: प्राप्त।

विदेश
दिवसीय
जनरल
० वर्ष की
मी चार
टेन द्वारा
फैसला।
विरोधी
तार।
नोग मरे,
रा नौवें
जापान में
लग्रेड में
लोकतंत्र
।
रेशन की
ई को रद्द
ा, ब्रिटेन
समर्पण।
ों को पुनः
पश्चिमी
समुद्र में
ांति और
वार करने
ादिवासी
हित तीन
जागरण
०० लोग
ं डूबने से
अमरीका
नन टेनिस
यों द्वारा
की हत्या।
रकार के
राष्ट्रपति
की जनता
। दक्षिण
दाधिकारी
ा।
ीलंका के
संविधान
ी नेशनल
सालों के
यता पुन

पम्प चले तो फ़सल फले
पम्प बंद तो काम मंद

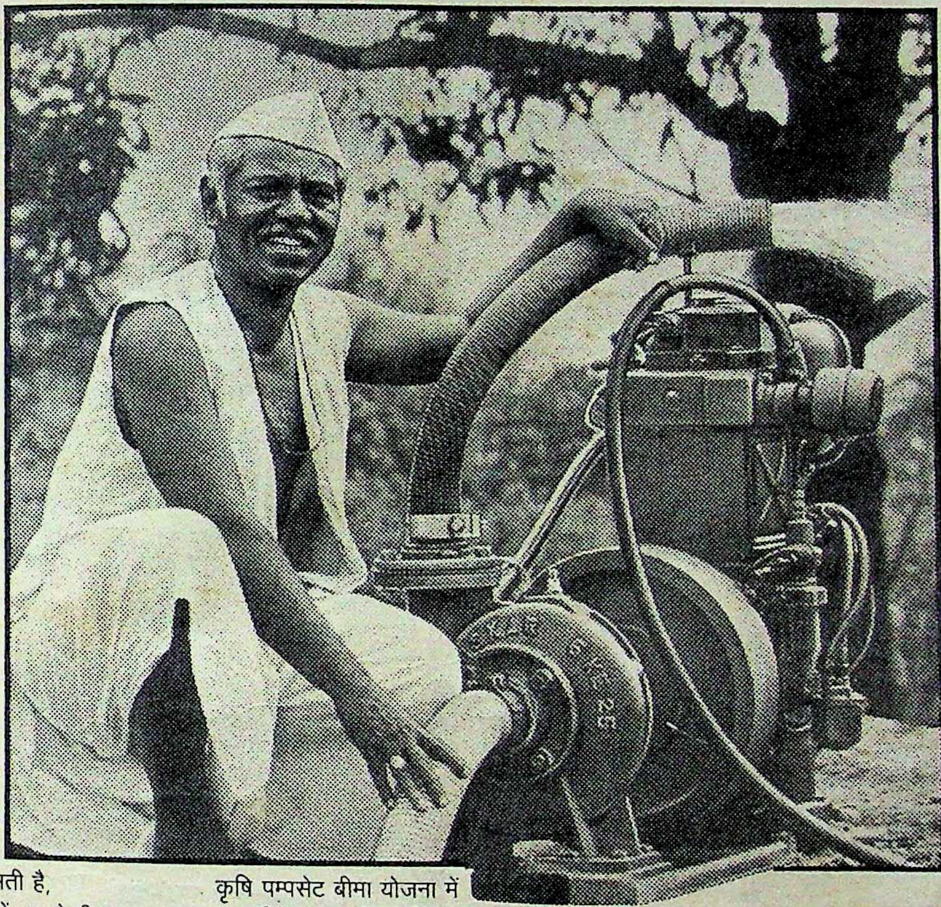

किसान की जान उसकी फ़सल में बसती है, तो फ़सल की पानी में. अच्छे बीज, अच्छी खाद और कमरतोड़ मेहनत सब बेकार हो जाएं अगर फ़सल को समय पर पूरा पानी न मिले.

खड़ी फ़सल को पानी की ज़रूरत हो, कुएं में पानी भी हो और ऐसे में पम्प जल जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए या चोरी हो जाए तो किसान तो बरबाद हो जाए.

ऐसी मुसीबत में किसान को सहारा देता है **न्यू इन्डिया का कृषि पम्पसेट बीमा.**

कृषि पम्पसेट बीमा योजना में सबमर्सिबल पम्पसेट सहित सभी तरह के पम्पसेटों का बीमा किया जाता है.

कृषि पम्पसेट बीमे की दर : मोटर की हॉर्स पावर के हिसाब से कम से कम 50 रुपये सालाना.

न्यू इन्डिया के 1000 से भी अधिक कार्यालय देशभर में फैले हुए हैं.

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीक के कार्यालय में पधारें या एजेंट से मिलें. आपकी सेवा के लिए दूरदराज़ के गांवों में भी न्यू इन्डिया के ग्रामीण प्रतिनिधि तैनात हैं.

R.K.SWAMY/NIA/4294/HN-A

कृषि पम्पसेट बीमे के लिए

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कंपनी

हर मुसीबत में आपका सहारा

तिवारीजी स्थिर रहेंगे !

दरबार के 'इडीएट बाक्स' यानी दूरदर्शन पर २ सितंबर की रात को मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर (एमजे अकबर) की कोशिश थी कि वे जो चाहते हैं, नारायण दत्त तिवारी वही किसी तरह से उगल दें, लेकिन तिवारी ने शालीनता की लक्ष्मण रेखा को लांघने से सफाई से इनकार कर दिया। अकबर के एक प्रश्न का लहजा कुछ ऐसा था, "क्यों पंडत, यह बताओ आपकी निगाह दरबार की कुरसी पर क्यों लगी हुई है?" लेकिन तिवारीजी ने आहिस्ता से सवाल को चलता कर दिया। उसके पहले जब अकबर ने तिवारीजी को पटकनी मार कर यह कहलाने की कोशिश की कि राजा मांडा (वीपी सिंह) बेईमान हैं, तो नारायण दत्त ने हाथ जोड़ लिये।"

दिल्ली दरबार में इस बात को लेकर अकबर का काफी दबदबा है कि वे अपने तीखे प्रश्नों से पेट की बातों को तुरंत निकलवा लेते हैं। उस रात मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के जब सारे दांव खाली गये, तो अंत में उन्होंने तिवारी के जवाब समेट कर दरबार के हवाले यह कहकर कर दिये, "इनमें से ढूंढ़ लिया जाये कि नारायण दत्त तिवारी की निगाहें, क्या दिल्ली दरबार की कुरसी पर लगी हुई हैं।" यों तो दरबार में काफी दिनों से खोजबीन चल रही है कि नारायण दत्त तिवारी के क्या इरादे हैं। पहले वीर बहादुर सिंह अफवाहें लाते थे। उनके स्वर्गवास के बाद गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाये बलराम सिंह यादव इस बात की तलाश कर रहे हैं कि तिवारी क्या कर रहे हैं? तिवारी ने पहले बाबू राम नरेश यादव को दरबार के चरणों में लाकर यह सफाई दी कि 'नहीं हुजूर, मैं तो आपका सेवक हूं। दरबार की कुरसी मेरे लिए बहुत पूजनीय है। उस पर निगाह गड़ाना, मुझ जैसे सेवक के लिए संभव नहीं।" मामला जमा नहीं, क्योंकि वीर बहादुर सिंह जिंदा थे। उसके बाद तिवारी ने कमला बहुगुणा को ले जाकर दरबार में खड़ा कर दिया। लेकिन 'शक' टस-से-मस नहीं हुआ। उसके बाद तिवारी ने राजा मांडा के घर में सेंध लगाकर जफर अली नकवी को उठवा लिया और दरबार के सामने पेश कर दिया, "हुजूर, जफर के आपके दरबार में आ जाने से अब राजा बिलकुल टूट जायेगा।" दरबार ने खुशी जाहिर करने के बजाय नाराजगी जाहिर की, "डंपी को तो भगा दिया, जो कुछ मादरे जुबान में बोलता है। इस चूजे को ले आये जिसमें छटांक भर गोश्त भी नहीं निकलेगा।"

तिवारी ने लखनऊ पहुचने के बाद अकबर अहमद 'डंपी' को कसा, "मियां तुम मुझे मरवा ही दोगे। अब नैनीताल की ठेकेदारी छोड़ो, उसमें तुमने काफी कमा लिया है। मेरे साथ चलकर दरबार में हाजिर हो जाओ। वहां तुमको बजाने के लिए ड्रम मिलेगा।" डंपी ने गलती से बंद हो गये कुरते के बटनों को खोला और मादरे जुबान में बोलना शुरू कर दिया, "चचा, मुझे अगर दरबार का ड्रम पीटना होता, तो मैं मेनका को लेकर बाहर ही क्यों निकलता। चूंकि अब चचा आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे कुछ गौर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं पिकनिक के लिए लंदन जा रहा हूं। वहां से लौटने के बाद बात करूंगा।" डंपी को रोकने की कोशिश तिवारी ने की, लेकिन डंपी ने कहा, "लंदन जाने से मत रोको चचा, अरे मैं अपने बाप की नहीं सुनता हूं, तो आप किस खेत की मूली हैं।" तिवारी ने अपना मन मसोस लिया, "जाओ मियां, जरूर जाओ। लेकिन तुमको भी ऐसी जगह मारूंगा कि पानी नहीं मिलेगा।" यह बात तिवारी ने मन-ही-मन कही। डंपी उचक कर लंदन को उड़ लिये।

लखनऊ सचिवालय की एनेक्सी में तिवारी गुमसुम बैठे थे कि नरेंद्र सिंह बिजली के तारों से 'स्पार्क' करते हुए घुस आये,

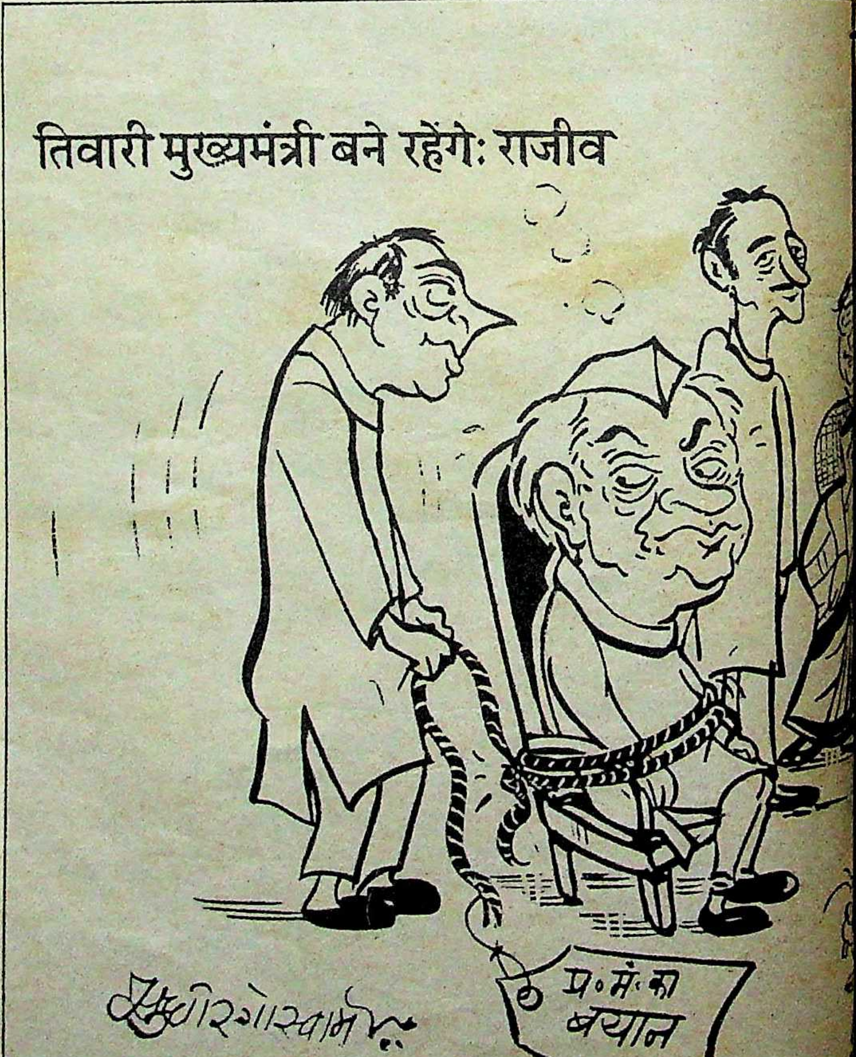
तिवारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे: राजीव
प्र० मं० का बयान
सुधीर गोस्वामी

"तिवारीजी, टिकैत पर डोरे डालना तो काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके खास चमचों को अपनी तरफ मिलाने में काफी सफलता मिल चुकी है। जो काम वीर बहादुर नहीं कर पाये, वह आप करके दिल्ली दरबार को अपना मुरीद बना सकते हैं।" तिवारी चुप रहे, तो नरेंद्र सिंह ने आहिस्ता से तिवारी के दर्द में शामिल होने की कोशिश की, "समझ रहे हैं, सर, आपका दर्द समझ रहे हैं। जो तीन बेर (वित्तमंत्री के रूप में) खाते थे, वे तीन बेर (मुख्यमंत्री के रूप में) खाते हैं।" नरेंद्र सिंह ने तिवारी के मूड को भांप लिया, "आप चिंता कर रहे हैं कि डंपी अगर ललित सूरी के जरिये दरबार में पहुंच गया, तो दरबार में आपकी किरकिरी हो जायेगी। सर' आप चिंता न करें। मैंने भी चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर राजनीतिक दांवपेंच सीखे हैं। अगर डंपी सेर हैं, तो आपका नरेंद्र सिंह सवा सेर है। ऐसा दांव मारूंगा कि डंपी को छठी का दूध याद आ जायेगा।" तिवारी इसके बाद भी खामोश रहे। नरेंद्र सिंह खिसियायी सी हंसी हंसते हुए बोले, "तिवारीजी आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा गुण है।" तिवारी खामोश ही रहे। नरेंद्र सिंह उठकर बाहर चले आये, "नारायण दत्त तिवारी की थाह का पाना ब्रह्मा के बस में नहीं है, यह दिल्ली दरबार और बावर्ची-खबरची क्या पायेंगे।"

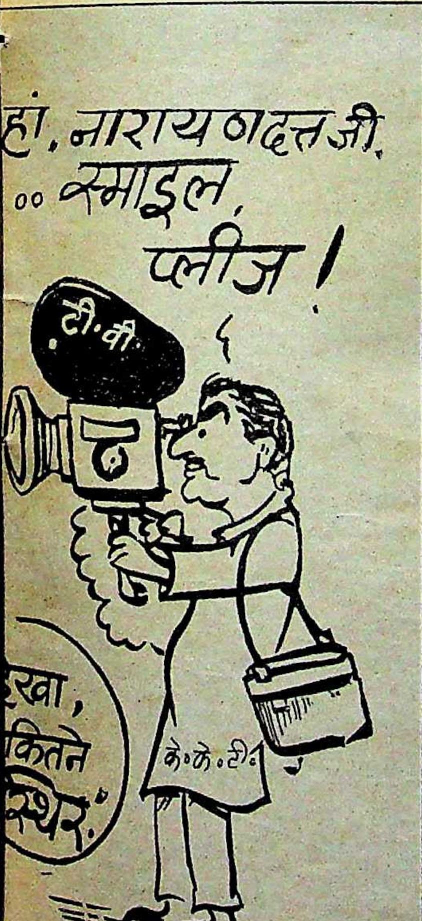
हां, नारायणदत्त जी, ... स्माइल, प्लीज!
टी.वी.
द
खा, कितने स्थिर.
के.के.टी.

बिसात बिछ चुकी थी। डंपी लंदन से दिल्ली में आ गिरे थे। ललित सूरी ने वाया कैप्टन सतीश शर्मा दिल्ली दरबार से संपर्क साध लिया था। बलराम सिंह यादव वाया गुलाम नबी आजाद परायी आग में हाथ सेंक रहे थे, "अब तिवारी को पता चलेगा कि दलबदल में उनकी ही महारथ नहीं है। डंपी को दिल्ली दरबार सीधे इंका पिंजड़े में कैद करेंगे। तिवारी देखते रह जायेंगे।" तिवारी दिल्ली के दो जंतर-मंतर में खामोश बैठे थे। डंपी ने दो नावों में सवारी कर रखी थी। एक ओर अपने पुराने सखा ललित सूरी के जरिये दरबार में पहुंचने की तथा दूसरी ओर नारायण दत्त तिवारी के माध्यम से कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम बना रखा था। लेकिन डंपी का दिल चंद्रशेखर के यहां गिरवी था। वे यह भी सोच रहे थे कि अगर चंद्रशेखर राजा मांडा के खिलाफ खड़े हो जायें, तो यहीं रह कर वे अपनी मादरे जुबान में संजय सिंह पर अपना नजला निकाल लें। लेकिन चंद्रशेखर के खेमे में गहरी खामोशी थी। डंपी को खामोशी बिलकुल पसंद नहीं है। इसलिए वे चंद्रशेखर के नार्थ एवेन्यू बंगले से भाग खड़े हुए। सब कुछ बहुत गोपनीय ढंग से चल रहा था। तिवारी खामोश थे। ललित सूरी खामोश थे। डंपी अपनी जुबान पर ताला डाले बिलकुल खामोश थे। लेकिन बिसात बिछी हुई थी और गोटियां बड़ी खामोशी से चली जा रही थीं।

दिल्ली दरबार से ११ सितंबर की तारीख तय कर ली गयी कि डंपी को उस दिन कांग्रेस के पिंजड़े में आने की अनुमति दे दी जाये। गुलाम नबी यूपी के इंचार्ज थे। लेकिन उनको कतई पसंद नहीं था कि डंपी कांग्रेस में आयें। उन्होंने कहा भी कि जब संजय गांधी जिंदा थे, तो डंपी ने उनको किसी करवट नहीं सोने दिया। अब वे फिर आ रहे हैं, उनकी नींद हराम करेगा। लेकिन गुलाम की एक नहीं सुनी गयी।

जब जफर अली नकवी को कांग्रेस में लाया जा रहा था, तो डंपी ने गहरी चाल चल दी थी, जिससे दरबार को शह लगी थी। सारा दोष नारायण दत्त तिवारी पर आया था कि उन्होंने जानबूझ कर दरबार को डंपी के हाथों शह दिलायी। इस पर तिवारी बहुत-सोच-समझ कर चालें चल रहे थे। यश मिले या न मिलें, अपयश नहीं मिलना चाहिए।— तिवारी की पूरी राजनीति यही थी। ९ सितंबर को शाम को जनता दल में यह खबर पहुंचा दी गयी कि डंपी ११ सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राजा मांडा तुरंत हरकत में आ गये। पहले तो यह तय हुआ कि दिल्ली से डंपी को पार्टी से निलंबित कर दिया जाये। लेकिन फिर अरुण नेहरू ने सुझाया, "यूपी यूनिट को यह काम सौंप दो। अगर दिल्ली से यह काम किया गया, तो डंपी हम लोगों को बहुत गालियां देगा।" राजा मांडा ने तुरंत मुलायम सिंह को फोन किया। मुलायम सिंह ने पहले तर्क दिया कि दिल्ली से डंपी को निकाल दो। मैं क्यों उसकी गालियां सुनूं।" राजा ने जब मुलायम सिंह को समझाया, तो उन्होंने यह काम अपने एक महामंत्री रामपाल सिंह को सौंप दिया। रामपाल सिंह ने डंपी को पार्टी से निकाल दिया। डंपी त्रिशकु की तरह हवा में लटक वे भाग कर तिवारी के पास गये, "चचा, यह डबलपन किसका है?" तिवारी ने डंपी के कंधे पर हाथ फेरा, "घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दल-बल के साथ दिल्ली चलो। सब ठीक हो जायेगा। इंका के पिंजड़े में दाखिल होने के पहले तुम्हारी मुलाकात दिल्ली दरबार से होगी।" डंपी एक वातानुकूलित बोगी में अपने दल-बल के साथ दिल्ली ११ सितंबर की सुबह पहुंचे। तिवारी ने काफी कोशिश की कि डंपी शहीद होने के पहले दरबार के दीदार हासिल कर लें। लेकिन सरकार से साफ मनाही हो गयी कि 'दरबार को फुर्सत नहीं है।" ११ सितंबर की शाम को इंका मुख्यालय में जो खबरची सम्मेलन डंपी को कांग्रेस पिंजड़े में बंद करने के लिए हुआ, उसमें एक ओर गुलाम नबी आजाद नहीं थे, तो दूसरी ओर नारायण दत्त तिवारी भी नहीं थे। विट्ठल गाडगिल और बलराम सिंह यादव ने डंपी को इंकाई पिंजड़े में पहुंचाने की रस्म अदायगी की। डंपी इंका के पिंजड़े में जैसे ही दाखिल हुए, उनको बजाने के लिए कांग्रेस ड्रम दे दिया गया। डंपी अब कांग्रेसी ड्रम बजायेंगे। इधर १५ सितंबर को दिल्ली दरबार ने अलीगंज (उप्र) में सार्वजनिक घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ही रहेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कि तीन साल बाद मैं यहां आऊंगा और तिवारीजी मुझे आमंत्रित करेंगे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री को इस सार्वजनिक मुनादी की आवश्यकता क्यों पड़ी?

—दरबारी लाल

राजनीति के चौपड़ पर किसका खेल चौपट

माया... सच के दरवाज़े की चौखट

राजनीति के चौपड़ पर किसका पासा उलटा पड़ता है? किसका सीधा? कौन उखड़ता है? कौन जड़ पकड़ता है? कौन से बादल गरजते हैं, कौन से बरसते हैं? कौन सिक्का खोटा है, कौन चना थोथा है... यह केवल बातों की चाट नहीं, बल्कि सचाई की थाह तक पहुंच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है-माया।

आज की बात बनती है कल का इतिहास और माया अपना राष्ट्रीय दायित्व समझकर निष्पक्ष व निडर भाव से पाठकों को सचाई से अवगत कराती है। राजनीति के दांवपेच हों या समाज के कुचक्र सभी के लिए दुधारी तलवार, जिसका वार घातक के लिए घाव और आहत के लिए उपचार। माया, जिसने आज के भारत के लिए हिन्दी का परचम लहराया।

६० बरसों के अनुभव में पली, भारतीय संस्कारों में ढली...माया। हिन्दी के पाठकों की एकमात्र ऐसी समाचार पत्रिका जो हिन्दी में सोचती है और हिन्दी में बोलती है, क्योंकि हिन्दी ही आपकी और हमारी भाषा है।

माया... वह खबर देती है, जिसकी किसी को खबर नहीं होती।

सर्वाधिक बिकनेवाली समाचार पत्रिका
माया

जिसमें आज का भारत सिमट आया

Karishma/MAYA/10/2418 Hi

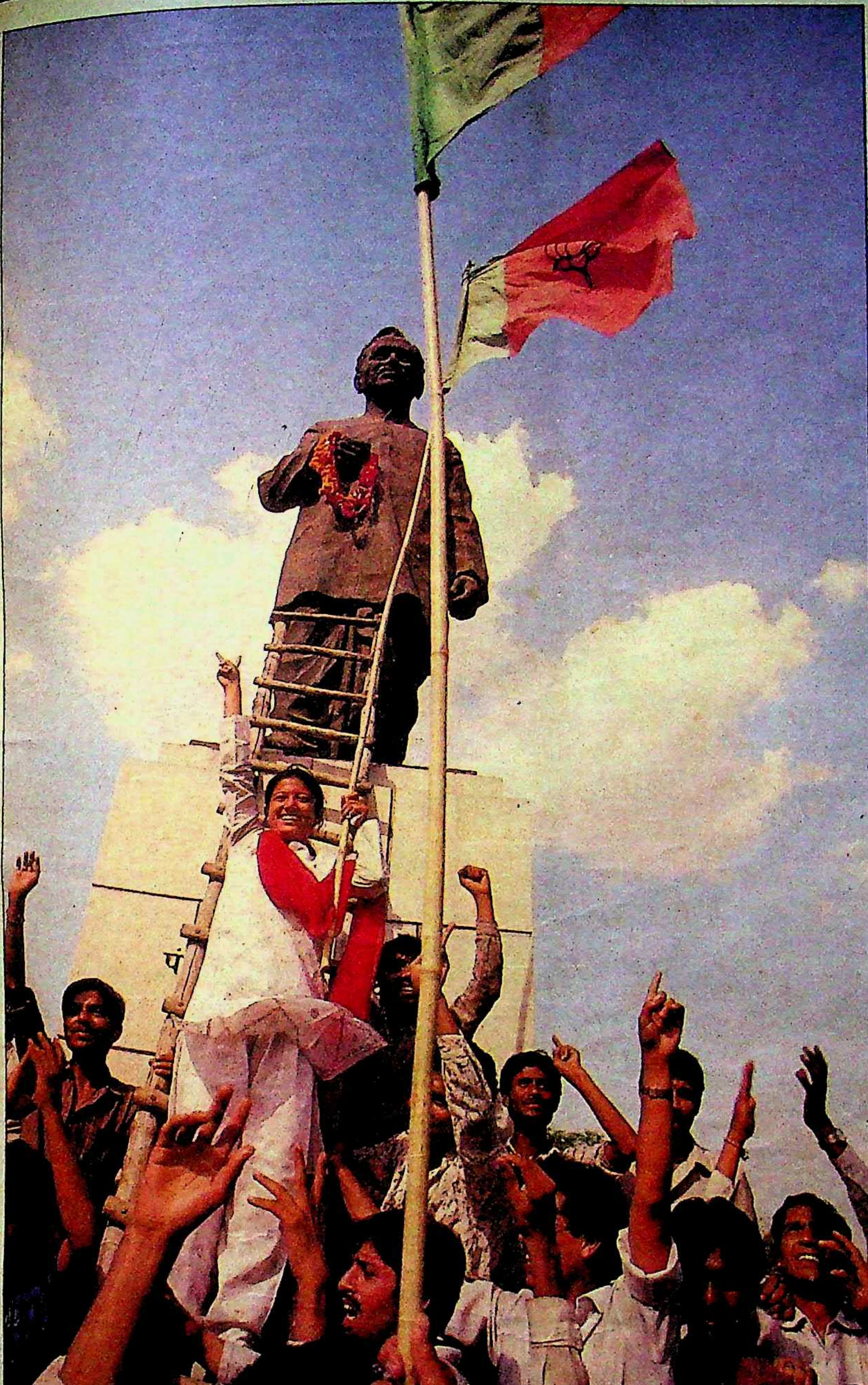

अंजु सचदेव दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बन गयी हैं। उनके अध्यक्ष बनने से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अंजु केवल इसलिए सुर्खियों में नहीं हैं कि वे छात्रसंघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, बल्कि वे विद्यार्थी मोर्चा से बगावत कर अध्यक्ष पद पर चुनी जानेवाली दूसरी उम्मीदवार भी हैं। इसके पूर्व १९८६ में मदन सिंह बिष्ट ने एनएसयूआई से बगावत करके चुनाव लड़ा था और अध्यक्ष चुने गये थे।

अंजु सचदेव के बागी हो जाने पर भाजपा ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन वे भाजपा के दरवाजे से बाहर होकर भी अपने भाजपा-प्रेम से विमुख नहीं हुई। तभी तो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाजपा के झंडे के नीचे अपनी जीत की खुशी जाहिर की और अपनी जीत को भाजपा, मदनलाल खुराना तथा विजय कुमार मल्होत्रा की जीत बताया।

छाया : एस पाल

AIDWA
AIDWA
जनवादी महिला
पुणे जिल्हा
AIDWA

लगभग पचीस हजार महिलाओं ने ८ सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया। यह रैली राजघाट से शुरू होकर करीब सात किलोमीटर की दूरी तय कर बोट क्लब तक पहुंची। ग्रामीण और शहरी महिलाएं रंगबिरंगी पोशाकों में थीं। उनके हाथों में लाल और सफेद रंग के झंडे और नारे लिखी तख्तियां थीं। रैली का आयोजन आल इंडिया वीमेंस एसोसिएशन और अखिल भारतीय कामगार महिला समिति की ओर से हुआ था। यह रैली देश भर में महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक थी, क्योंकि हर प्रांत की महिलाओं ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था।

महिलाओं की मुख्य मांगें थीं: रोजगार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाये, महिलाओं के लिए न्यूनतम वेतन लागू किये जायें और महिलाओं को पट्टे दिये जायें। इन मांगों के अतिरिक्त राजनीतिक मांगें भी थीं। बोट क्लब पर जनसभा में तब्दील हुई रैली में वक्ताओं ने राजीव सरकार को हटाने की मांग करते हुए कहा कि यह सरकार महिलाओं का भला नहीं चाहती। पंचायती राज और महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा चुनावी चाल है, क्योंकि इससे महिलाओं की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यदि सरकार महिलाओं का हित चाहती, तो बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत आजादी के बाद घटने के बजाय बढ़ता। आजादी के पहले जहां यह प्रतिशत ३४ था, वहां अब १४ रह गया है।

छाया : सुनील सक्सेना

जनवादी महिला समिति
फरीदाबाद

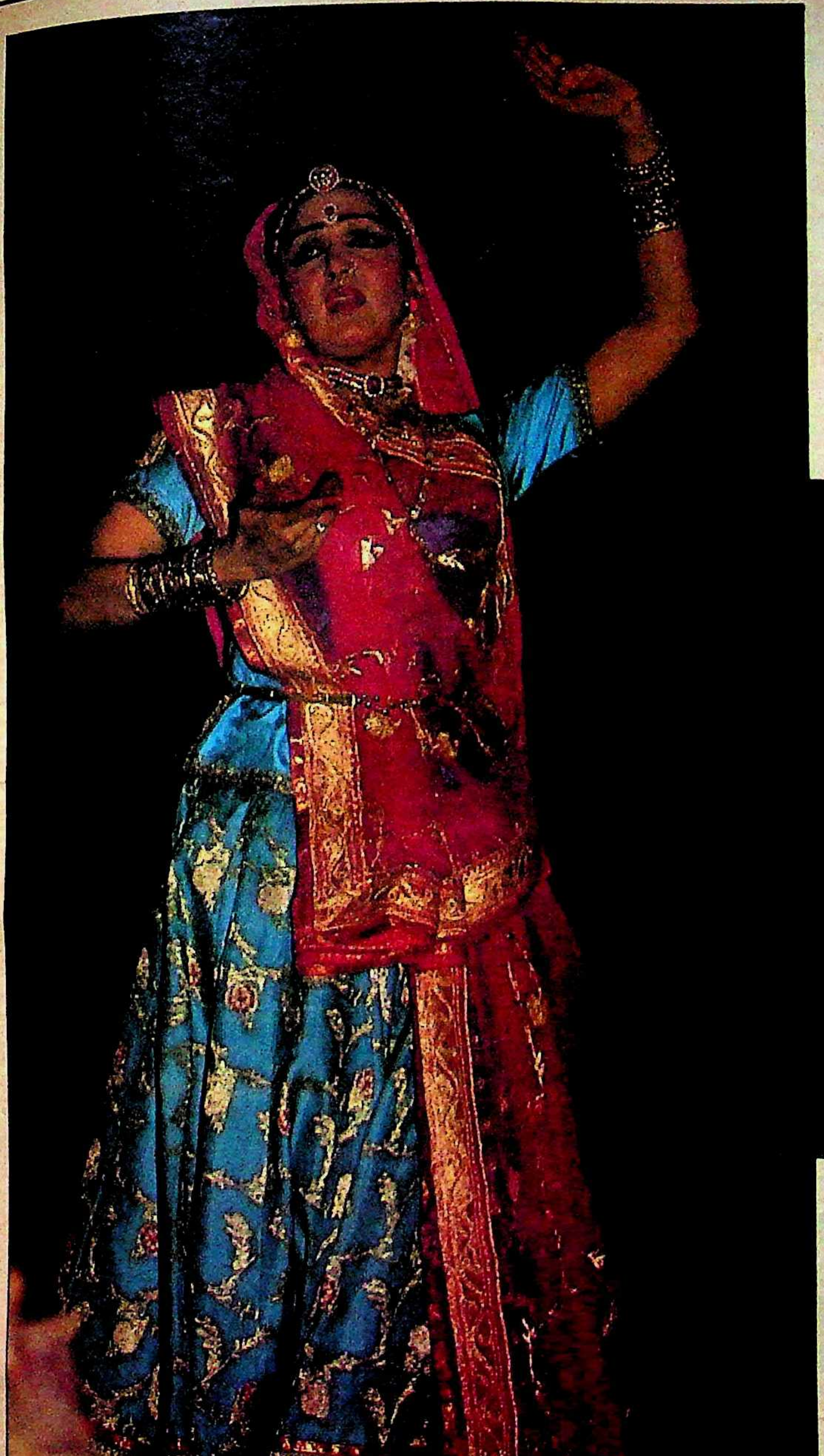

हेमामालिनी को बचपन से ही मीरा बनकर नाचने और अपने आराध्य देव को रिझाने का शौक रहा है। इसलिए जब गुलजार ने उनसे मीरा की भूमिका निभाने का आग्रह किया, तो उन्होंने दूसरे निर्माताओं को दी गयीं डेट्स को कैंसिल कर 'मीरा' फिल्म की शूटिंग की। बाद में उन्होंने 'मीरा' पर टीवी सीरियल बनाने की योजना बनायी, लेकिन मंडी हाउस की लालफीताशाही के कारण वह योजना फंसी रह गयी। जब वे फिल्मों में व्यस्त थीं, तभी से उनकी योजना मीरा पर एक नृत्यनाटिका तैयार करने की थी, जो इस जन्माष्टमी को पूरी हुई। उन्होंने इस्कान में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में इस नृत्य-नाटिका को प्रस्तुत किया। इसकी सफलता से प्रभावित हो वे इस नृत्य-नाटिका का प्रदर्शन पूरी दुनिया में करने को उत्सुक हैं। इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से विशेष प्रभाव पैदा करनेवाली इस नृत्यनाटिका को वे और भी वैज्ञानिक रूप देने की योजना बना रही हैं।

छाया : सुधाकर ओल्वे

छाया : राकेश सरावगी

'बहूजी' के नाम से विख्यात श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी बनारस की राजनीति की धुरी थीं और अपने श्वसुर पंडित कमलापति त्रिपाठी और पति लोकपति त्रिपाठी (उप्र के सिचाई मंत्री) की राजनीतिक गतिविधियों की सूत्रधार थीं। १९८४ में वे लोकसभा के लिए चंदौली क्षेत्र से चुनी गयी थीं और वाराणसी जिला कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी थीं। अनेक उतार-चढ़ावों, विवादों-अपवादों के झंझावात से अपने जीवट के बलबूते जूझते हुए बहूजी ने राजनीतिक भीड़ में अपनी अलग जगह बनायी थी। उन्होंने कभी हिम्मत हारना नहीं सीखा था, लेकिन ७ सितंबर की रात के नौ बजे दिल के दौरे ने उन्हें सदा-सदा के लिए मौन कर दिया। ८ सितंबर को उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनके औरंगाबाद निवास से शुरू हुई शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।

छाया : बलाउन

राजनीति का अपराधीकरण : माफिया युग की दस्तक

मधु लिमये

राजनीति का अपराधीकरण नये युग का प्रतीक है। भारतीय लोगों की आस्था व्यवस्थित राज्य की संकल्पना में नहीं है। व्यक्तिगत-पारिवारिक स्वार्थ तथा सार्वजनिक हित में साधारण भारतीय कोई फर्क नहीं करता। जब बड़े राजनीतिक नेता निजी स्वार्थ को ही राज्य का हित समझते हैं, तब इसमें क्या आश्चर्य कि साधारण आदमी कानून को ताक पर रखकर स्वार्थपूर्ति को ही अपना आदर्श समझता है? सामाजिक मूल्यों का और सार्वजनिक नैतिकता का इतना अवमूल्यन हो चुका है कि अपराधी लोगों के प्रति घृणा के बजाय अकसर आकर्षण और औत्सुक्य पाया जाता है। हमारी रंगीन पत्रिकाएं अपराधियों की नित्य आरती उतारती हैं और उनके क्रियाकलापों को रोमानी नजर से देखती हैं। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक जीवन में तथा राजनीति में अपराधियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा विभिन्न आर्थिक नियमों के कारण काले धन का निर्माण शुरू हुआ और पिछले चालीस वर्षों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण इसका अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हमारी राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा समानांतर तथा गैरकानूनी अर्थव्यवस्था में तैयार होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो काला धन पैदा होता है वह अवांछनीय जरूर है, पर कम-से-कम उसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के काम में तो किया ही जाता है। परंतु दूसरे किस्म का जो काला धन है वह नैतिक दृष्टि से न केवल अवांछनीय है, बल्कि राष्ट्रीय हित के लिये घातक भी है। इस धन का एक स्रोत है अवैध शराब और उसका वितरण, दूसरा स्रोत है मादक पदार्थों का वितरण। आज पाकिस्तान इस अवैध व्यापार का एक महत्वपूर्ण अड्डा बन गया है। दुर्भाग्य है कि हमारे नौजवानों में, और विशेषकर विश्व-विद्यालयी छात्रों में, इस तरह के मादक द्रव्यों का सेवन एक फैशन-सा बन गया है। इस प्रकार के काले धन के अन्य स्रोत हैं डकैती, लूटपाट आदि परंपरागत अपराध। चंबल से लेकर नर्मदा तक फैले इलाकों में ठगी, डकैती आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का बोलबाला अठारहवीं शताब्दी के मध्य से बढ़ रहा था। अंग्रेजी हुकूमत भी इसका पूरी तरह से दमन कर नहीं पायी। अपराधजनित धन का सबसे बड़ा स्रोत है तस्करी का व्यापार। भारत की भूमि सीमा कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम तक फैली हुई है। फिर भारत की समुद्र-सीमा भी काफी लंबी है। भूमि-सीमा तथा सागरी इलाके तस्करों के बड़े अड्डे हैं। तस्करी के जरिये अवैध धन का निर्माण और अपराधियों का फैलाव तेजी से हो रहा है।

आपराधिक और गैरकानूनी अर्थव्यवस्था के पनपने का एक बड़ा कारण है, बेरोजगारी। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात अकसर की जाती है, पर जब तक इन नौजवानों के प्रशिक्षण का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जायेगा, तब तक इन्हें काम कैसे मिलेगा? आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां कारीगरों की नितांत कमी है। लेकिन प्रशिक्षण और कौशल के बिना इस तरह के काम और व्यवसाय नौजवान नहीं कर पायेंगे। अपराधियों के गिरोह इन नौजवानों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इन गैरकानूनी गतिविधियों में नवयुवक एक किस्म के रोमांस का अनुभव करते हैं। काले धन के अनुपात के साथ-साथ इन क्रियाकलापों में मसरूफ नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है।

अपराधी गिरोहों का दायरा जब तक सीमित था, तब तक ये लोग प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहते थे। राजनीतिज्ञ चुनावों में इनकी शक्ति का—मसल पावर का—इस्तेमाल मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के लिए, वोटों को लूटने के लिए और पिछड़े तथा दबे हुए वर्गों को कुचलने के लिए करते थे। इसके एवज में अपराधियों को कानून के जाल से बचाने में राजनीतिज्ञ उनकी मदद करते थे। इस तरह अपराधी गिरोह, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही—पुलिस—का एक खतरनाक त्रिकोण सार्वजनिक जीवन पर हावी होने लगा है। हमारे देश की पुलिस-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अवांछनीय कार्य-क्षमता से इतनी ग्रस्त है कि लोकरक्षा का कार्य करने में वह पूर्णतया असफल हो चुकी है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी गिरोह तथा पुलिस बल दोनों में अपराधी तत्व घुस गये हैं। दोनों मिलकर जनता का भक्षण कर रहे हैं।

अपराधजनित धन की यह प्रारंभिक स्थिति थी। अब यह धन और अपराधी गिरोह इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि वे सोचने लगे हैं, राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू या सहयोगी बनने के बजाय हम स्वयं राजनेता क्यों न बनें? बाल ठाकरे की शिवसेना एक नये किस्म का 'राजनीतिक दल' है। इसमें अपराधी, गुंडे, माफिया आदि असामाजिक तत्वों को खुलकर प्रश्रय मिलता है। बदलते हुए माहौल का परिचय इस बात से मिलता है कि भाजपा जैसा मध्यमवर्गीय दल शिवसेना जैसी माफिया पार्टी के साथ खुलकर गठबंधन करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। जनता दल में कुछ अपवादों को छोड़कर शिवसेना के साथ समझौता करने की इच्छा है हालांकि वे इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहते।

खालिस तस्करी के जरिये धन इकट्ठा करनेवाला कुली मस्तान अब हाजी मस्तान बन गया है। उसने कई होटल आदि व्यवसाय खोले हैं और एक राजनीतिक दल भी बना लिया है। कांग्रेस में तो अपराधी तत्वों की ही भरमार है। यह नहीं कि जनता दल इस दोष से सर्वथा मुक्त है। कई जनता दल के नेताओं के अगल-बगल में अपराधी और माफिया पाये जाते हैं।

एक जमाना था जब हमारे नौजवानों ने अपने आपको ट्रेड यूनियन संगठन, सहयोगी संस्थाओं को आंदोलनों और युवा आंदोलनों के लिए समर्पित किया था। उनकी प्रेरणा आदर्शवादी थी। अब ट्रेड यूनियन और कोआपरेटिव आंदोलन न सिर्फ एक व्यवसाय, एक पेशा बन गये हैं, बल्कि इनमें और माफिया गतिविधियों में बहुत कम अंतर रह गया है। कुछ लोग अपने को ट्रेड यूनियनिस्ट जरूर कहते-कहलाते हैं, पर हैं वे विशुद्ध माफिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर निगमों के जो चुनाव संपन्न हुए, उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि अपराधी राजनीति कल्पना की खोज नहीं है। यह एक कटु सत्य है। महात्मा गांधी कहते थे कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग टालने के लिए एक-एक पैसे का हिसाब जनता को देना चाहिये। पर आज हम देख रहे हैं कि राजनेता इस मामले में जनता के प्रति अपने उत्तर-दायित्व को बिलकुल महसूस नहीं करते। बोफोर्स, कर्नाटक तथा बंबई आदि इलाकों के लैंड स्कैंडल (भूमि के घोटाले), अपराधी धन और अपराधी राजनीति ये व्यवस्थित राज्य के विनाश का एक मायने में पूर्वाभास दे रहे हैं। भारतीय राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी अपराधी राजनीति और अपराधी धन का मुकाबला समाजहित के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं करेंगे, तो २१वीं शताब्दी का प्रारंभ 'माफिया युग' साबित होकर रहेगा। ■

जब आप अपनी कड़ी मेहनत की कमा
अधिक खर्च करते हैं तो आपको यह जान

क्या आपको अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल हुई।

भारत में केवल हीरो साइकिल में ही घिसने वाले अत्याधुनिक विकसित कोल्ड फोर्जिंग तक्नीक द्वारा निर्मित पुर्ज़े लगाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप पुर्ज़ों में अधिक टिकाऊपन व सरलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता आ जाती है।

अत्याधुनिक ग्लायडो इलैक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण साइकिल के पुर्ज़ों जैसे चेनव्हील व क्रैंक्स, रिम्स, हैण्डलबार, हब्स और अन्य प्लेटिड पुर्ज़ों को चकाचौंध कर देने वाली चमक प्रदान करते हैं।

उसी भांति नितान्त आधुनिक इलैक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग प्लांट फ्रेम, चिमटा, मडगार्ड्स और चेन कवर को खरोंचें आदि न आने की क्षमता व चिकनी चमकीली फिनिश प्रदान करता है।

प्रत्येक के लिए उपयुक्त हीरो. हीरो प्रत्येक आयु वर्ग और प्रत्येक आय वर्ग के लिए चमकीले व भड़कीले रंगों की व्यापक वर्णछटा तथा आकर्षक व्यापक श्रृंखला में प्राप्य हैं. प्रत्येक साइकिल आपकी लागत का सही मूल्य प्रदान करती है. चयन आपका।

हीरो

दुनियाभर में नं० 1

1 HERO BICYCLES

हीरो अपनाएँ — नं० 1 होने का अनुभव पाएँ।

हीरो साइकिल्स लिमिटेड
लुधियाना (पंजाब)-साहिबाबाद (उ.प्र.)

हीरो जैट

कमाक ७०० रु. से भी
ानका पूर्ण अधिकार है कि

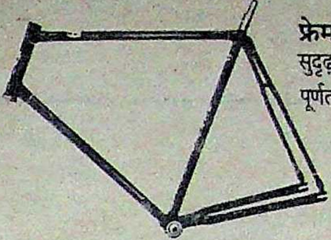

फ्रेम :
सुदृढ़ व
पूर्णतया संतुलित

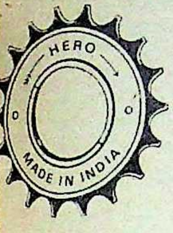

फ्रीव्हील :
हाई कार्बन व हाई क्रोम स्टील
बाल्स से युक्त

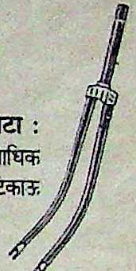

चिमटा :
झटके सहने में अत्याधिक
समर्थ एवं टिकाऊ

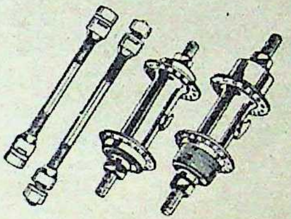

हब्स :
घर्षण रहित व सरल गति
के अनुरूप निर्मित

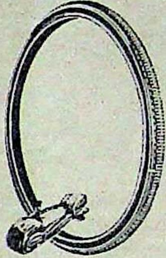

टायर्स और ट्यूब्स :
अधिक समय तक चलने के लिए
बढ़िया रॉ-मैटीरियल द्वारा निर्मित

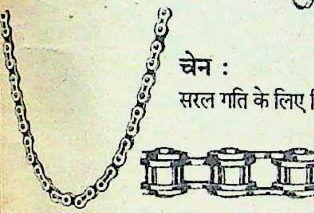

चेन :
सरल गति के लिए विशेषतः निर्मित

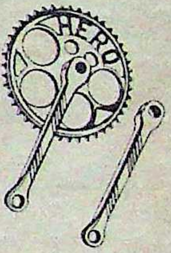

चेनव्हील और क्रैन्क :
सरल सवारी के लिए ही निर्मित.
पैडल की बढ़िया फिटिंग के लिए
क्रैंक्स में परिपूर्ण कटी चूड़ियाँ

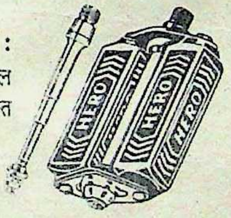

पैडल्स :
हाई कार्बन व हाई क्रोम स्टील
बाल्स से युक्त

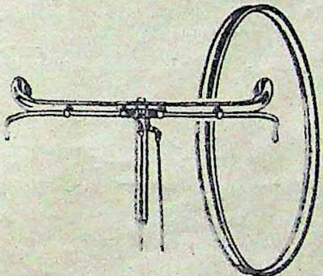

हैण्डलबार :
सरलता से चलाने के लिए
हैण्डलबार की उपयुक्त
बनावट

रिम्स :
रिम्स के जोड़ मज़बूत लगे
होने के कारण पूर्णतया
परिपूर्ण व टिकाऊ.

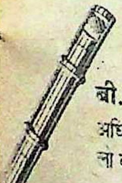

बी.बी. एक्सल :
अधिक टिकाऊपन के लिए
लो कार्बन स्टील द्वारा निर्मित

हीरो रॉयल
तुरन्त ब्रेक के लिए कुशल कारीगरी
द्वारा निर्मित सेन्टर-पुल ब्रेक्स तथा
चमकीले सुन्दर डिम्पल फोर्क द्वारा
सुसज्जित.

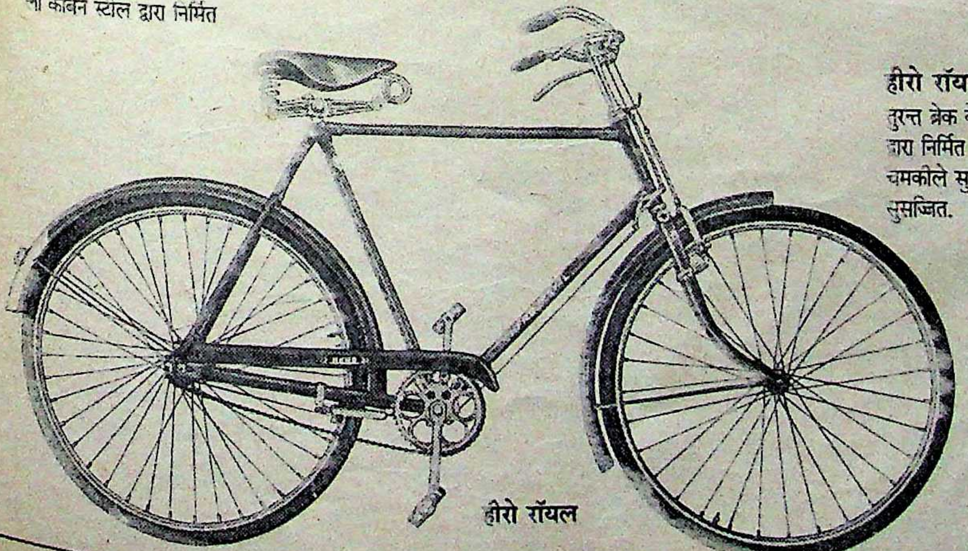

हीरो रॉयल

HC-NP-210

सिंहानिया घराना और सरकार

बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि जब किसी एक व्यापारिक घराने के नियंत्रण में चलनेवाली कंपनियों की परिसंपत्ति तथा बिक्री की गणना की जाती है, तो परिवार को ही मद्देनजर रखा जाता है। यानी ऐसी गणना करते समय इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि परिवार-जन एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं अथवा परिवार के सदस्यों के बीच स्वाभाविक संबंध तथा परस्पर सहयोग कायम है या नहीं।

यदि सिंहानिया परिवार की परिसंपत्ति तथा बिक्री की गणना उपर्युक्त पैमाने को मद्देनजर रखते हुए की जाये, तो पता चलता है कि १९८७-८८ में इस घराने के पास १५६६ करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्ति थी तथा उस समय यह घराना देश का चौथा बडा पारिवारिक घराना था। उस दौरान सिंहानिया परिवार अंबानी घराने से ४३७ करोड़ रुपए से पीछे तथा थापर परिवार से २१९ करोड रुपए से आगे था। यही नहीं, १९८७-८८ में सिंहानिया परिवार देश के उन छह व्यापारिक घरानों में से एक था जिनके पास १००० करोड रुपए मूल्य या उससे ज्यादा की परिसंपत्ति थी।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि यदि सिंहानिया परिवार की उपर्युक्त उपलब्धि को ही सामने रखा जाये, तो भी यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि निस्संदेह सिंहानिया परिवार कुशलता के एतबार से भी देश के शीर्षस्थ उद्यमी घरानों में से एक है, क्योंकि १९८० में ही इस परिवार की स्थिति यह थी कि इसकी गणना उद्यमी घरानों में दसवें स्थान पर थी। किंतु सात सालों के अल्पकाल में इस घराने ने अपनी कार्यकुशलता के ही बलबूते देश में चौथा स्थान हासिल किया तथा उसकी परिसंपत्ति १९८० की ४१२.७२ करोड के मुकाबले बढ़कर १५६६ करोड़ रुपए मूल्य की हो गयी।

दूसरा रुख: अब आइये तस्वीर के दूसरे रुख का जायजा लिया जाये। निस्संदेह परिसंपत्तियों तथा बिक्री के आधार पर सिंहानिया देश के उद्यमी घरानों में चौथे नंबर पर पहुंच गये, किंतु यदि इस घराने के वार्षिक मुनाफों का अवलोकन किया जाये, तो स्थिति पूरी तरह से भिन्न सामने आती है। १९८१ में कर अदायगी से पूर्व सिंहानिया घराने का कुल वार्षिक लाभ मात्र १८.२१ करोड़ रुपए था। यही नहीं, १९८७-८८ में जब इस परिवार की विभिन्न कंपनियों के उत्पादों की बिक्री १९८० के ४३६ करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर १३४७ करोड़ रुपए हो गयी, तो इस परिवार का वार्षिक लाभ घटकर मात्र ५.६२ करोड़ रह गया।

ऐसे में किसी का अकस्मात यह सवाल पूछ बैठना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अपनी जगह तर्कसंगत है। क्योंकि जब कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है, तो मुनाफा बढ़ने के बजाय घटना वाकई अस्वाभाविक है। इस सवाल के जवाब में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बिक्री बढ़ने के बावजूद मुनाफा घटने के पीछे कारण यही है कि चीजों के उत्पादन मूल्य के मुकाबले बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई या हुई भी तो उस दर से नहीं हुई जिस दर से उत्पादन मूल्य बढ़ा। इसके अतिरिक्त लाभ में बढ़त न होने के दूसरे कारणों से उद्यमी भलीभांति परिचित हैं।

यहां पर इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि कभी-कभार उत्पादन मूल्य में जो आकस्मिक बढ़त दिखायी देती है, वह वास्तविक नहीं होती। ऐसा तभी होता है जब कंपनी की अचल संपत्ति (मशीन, भवन आदि) का अवमूल्यन अनुमान से अधिक बढ़ जाता है। हालांकि यह सिर्फ कागज पर ही होता है तथा अवमूल्यन तभी दर्शाया जाता है जब सरकार उसको दर्शाने की अनुमति देती है। असल में यह रास्ता अपनाकर लाभ की मात्रा घटा दी जाती है। तथा कंपनी को कम 'कर' अदा करना पड़ता है। किंतु उत्पादन मूल्य घटने की उपर्युक्त स्थिति से सिंहानिया घराने के घटते लाभ को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता।

उठते सवाल: ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लाभ घटने का फिर और क्या कारण हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ते समय अचानक यह तथ्य सामने आता है कि अब एक सिंहानिया परिवार सभी कंपनियों की देख रेख नहीं कर रहा है। बल्कि यह घराना तीन परिवारों में बंट गया है तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य अपनी अपनी कंपनियों की देखरेख स्वतंत्र रूप से कर रहे

सिंहानिया परिवार

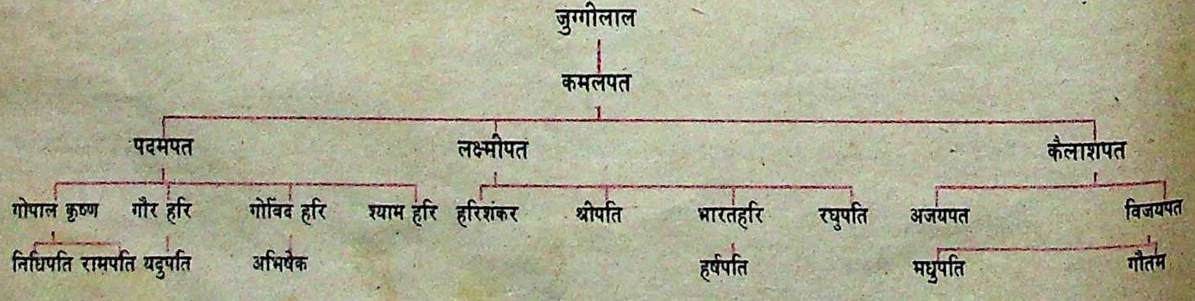

कंपनियां
जेके सिंथेटिक्स
जेके काटन
जेके जूट
जेके टेक
जेके एरोमेटिक्स

कंपनियां
स्ट्रा प्रोडक्ट्स
जेके इंडस्ट्रीज
उड़ीसा सिंथेटिक्स

कंपनियां
रेमण्ड इंडस्ट्रीज
रेमण्ड सिंथेटिक्स
इंडियन क्रोनिकल
जेके हिलीन करटिस
जेके टाइल्स

साभार 'बिजनेस इंडिया'

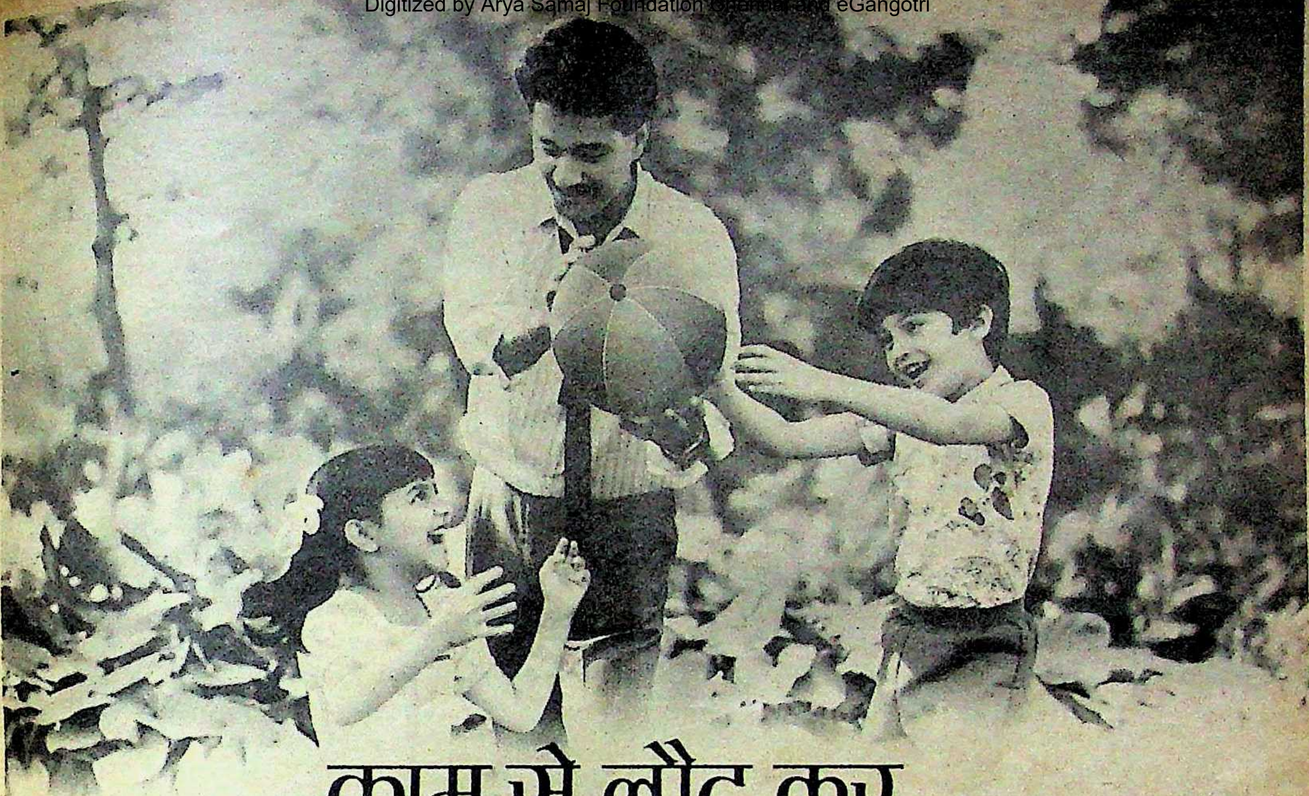

काम से लौट कर... हँसी-खुशी के पल!

ज़िन्दगी की भागदौड़, और दफ़्तर में काम का दबाव। पर शाम घर लौटने पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और आपके पति बच्चों के संग उत्साह और उमंग के साथ व्यस्त हो जाते हैं।

इसका श्रेय आपको है। क्योंकि आप दिन-भर चुस्ती और शक्ति के लिए उन्हें रोज़ हॉर्लिक्स जो देती हैं।

"हॉर्लिक्स में अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ—होते हैं जो शरीर को शक्ति, चुस्ती और तन्दुरुस्ती देते हैं। दिन-भर अच्छे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर बने रहने के लिए।"

Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nourisher
PROTEINS ✓
VITAMINS ✓
MINERALS ✓
CARBOHYDRATES ✓
CALCIUM ENRICHED ✓
EASY TO DIGEST ✓
ENERGY SOURCE ✓
COMPLETELY NATURAL ✓

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6224 HIN

हैं। सिहानिया घराने के जो तीन परिवार देश के इस बड़े उद्यमी घराने का कामकाज देख रहे हैं, वे हरिशंकर सिहानिया, विजयपत सिहानिया तथा गौर हरि सिहानिया के परिवार हैं।

इस घराने की महत्वपूर्ण कंपनियां—स्ट्रा प्रोडक्ट्स तथा जेके इंडस्ट्रीज—हरिशंकर सिहानिया के नियंत्रण में हैं। यही नहीं, बहुत-सी जूट मिलें भी हरिशंकर की देखरेख में चल रही हैं, किंतु ये मिलें हरिशंकर के लिए मुनाफे की इकाइयां न होकर मुसीबत ही साबित हुई हैं। इसी तरह विजयपत सिहानिया रेमण्ड तथा जेके हिलीन करटिस की निगरानी कर रहे हैं। विजयपत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के एक बडे समाचार-पत्र इंडियन पोस्ट के भी मालिक हैं। हाल में इंडियन पोस्ट काफी चर्चा में था, क्योंकि इस पत्र के संपादक ने सिर्फ इसलिए पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उसे इस बात के निर्देश दिये गये थे कि वह सत्तारूढ दल के महत्वपूर्ण लोगों तथा उनके दोस्तों के बारे में कुछ आपत्तिजनक न लिखे। सिहानिया घराने के तीसरे परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं गौर हरि सिहानिया। इनके नियंत्रण में चल रही प्रमुख कंपनी जेके सिंथेटिक्स है, जिसे हाल में उत्तर प्रदेश के सलेमपुर नामक स्थान पर पेट्रोकेमिकल परियोजना का लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

यहां पर इस बात को भी स्पष्ट करना जरूरी है कि हरिशंकर, विजयपत तथा गौर हरि सिहानिया चचेरे भाई हैं। गौर हरि सिहानिया पदमपत सिहानिया के बेटे हैं, जबकि हरिशंकर लक्ष्मीपत सिहानिया के सुपुत्र हैं। इसी तरह विजयपत सिहानिया कैलाशपत के बेटे हैं। उक्त तीनों पिता कमलपत सिहानिया के बेटे हैं जिनके पिता जुग्गीलाल, सिहानिया साम्राज्य के संस्थापक थे। (देखें चार्ट) मजे की बात यह है कि हरिशंकर, विजयपत तथा गौर हरि रिश्ते से चचेरे भाई जरूर हैं, किंतु इनके बीच व्यापारिक-सहयोग नाम मात्र का भी नहीं दिखायी देता। जबकि आमतौर से मित्रता का खयाल करके ही एक उद्योगपति दूसरे की मदद करने को तत्पर होता है। व्यापारिक-सहयोग की बात तो एक ओर रही, अकसर इन चचेरे भाइयों के बीच तनाव की स्थिति भी बनती रही है।

सरकारी सहानुभूति: हालांकि हाल में सरकार ने सिहानिया परिवार के प्रति जो सहानुभूति दिखायी है, उससे तीनों परिवारों के बीच आपसी सहयोग के नये द्वारा खुले हैं। गौर हरि को सलेमपुर परियोजना हेतु लाइसेंस देने के साथ-साथ सरकार ने स्ट्रा प्रोडक्ट्स के मालिक हरिशंकर सिहानिया को भी लीनियर-एलकाथिल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन का लाइसेंस दिया है। इसी तरह रेमण्ड कंपनी के स्वामी विजयपत सिहानिया को पालियस्टर फिलामेंट यार्न बनाने का लाइसेंस सरकार से प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है तीनों भाइयों को सरकार से जिन तीन रसायनों के उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, उसकी वे आपस में ही खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। तीनों रसायन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए आवश्यक हैं और तीनों भाई इसी इंडस्ट्री में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तीनों परिवारों के व्यापार का फलना-फूलना लाजिमी है।

मिसाल के तौर पर जेके एरोमेटिक्स की प्रतिवर्ष १५०,००० टन प्योर टेरेप्थेलिक एसिड (पीटीए), ३०,००० टन बेंजीन तथा इतनी ही मात्रा में आरथाक्सी आरथोलिक्जीन के उत्पादन की योजना है। निस्संदेह उपर्युक्त तीनों रसायनों की देश में अच्छी खपत है। जेके एरोमेटिक्स से पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज टेरेप्थेलिक एसिड का उत्पादन कर रही हैं तथा इसी रसायन के उत्पादन से रिलायंस का भविष्य उज्ज्वल हुआ है।

ऐसे में चूंकि जेके सिंथेटिक्स तथा उड़ीसा सिंथेटिक्स को पीटीए की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये कंपनियां अगर चाहेंगी, तो अपने ही घराने की जेके एरोमेटिक्स कंपनी से पीटीए खरीद लेंगी। इसी तरह विजयपत सिहानिया की रेमण्ड सिंथेटिक्स भी जेके एरोमेटिक्स से पीटीए प्राप्त कर सकेगा। यही नहीं, हरिशंकर सिहानिया की एलएबी परियोजना के लिए बेंजीन की आवश्यकता होगी। यदि वे चाहेंगे, तो गौर हरि की जेके एरोमेटिक्स उन्हें बेंजीन उपलब्ध करा देगी। कहने का मतलब यह है कि तीनों परिवार आपस में ही अपने उत्पादों की खरीद-फरोख्त करके तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। किंतु सवाल यह है कि इन तीनों परिवारों के बीच भविष्य में क्या आपसी सहयोग पैदा होगा? अब तक तो हाल यह रहा है कि प्रत्येक परिवार केवल अपने ही हित को सामने रखकर काम करता आया है।

यदि तीनों परिवार सूझ-बूझ तथा परस्पर सहयोग की बात को सामने रखते हुए काम करेंगे, तो निस्संदेह इस घराने का भविष्य उज्ज्वल है, किंतु यदि तीन नयी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राप्त करने के बाद भी तीनों परिवारों में आपसी सहयोग का अभाव रहा, तो इस घराने का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा।

सहयोग की आशा: हाल की तब्दीलियों तथा नयी परियोजनाओं को मद्देनजर रखते हुए व्यापारिक खेमों में इस बात की चर्चा है कि तीनों सिहानिया परिवार अब परस्पर सहयोग के लिए तैयार हैं तथा पिछली गल्तियों को नजरअंदाज करके तीनों चचेरे भाइयों ने एक-दूसरे की मदद करने की कसम खायी है। अपने इस नजरिये को मजबूत करने के लिए उद्यमी यह मिसाल पेश करते हैं कि यदि तीनों परिवारों में परस्पर सहयोग की आशा न जगी होती, तो लगभग एक ही समय में सरकार तीनों परिवारों को ऐसी परियोजनाओं का लाइसेंस न देती जिसमें एक-दूसरे की मदद से जल्द तरक्की के आसार नुमाया हैं। 'फिर तीनों परिवार ही ऐसी चीजों का उत्पादन करने जा रहे हैं जो पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित हैं।

यही नहीं, कुछ उद्यमियों का तो यह भी मानना है कि सिहानिया परिवार के व्यापार में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे आये हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में हैं। उल्लेखनीय है कि सिहानिया परिवार को सलेमपुर परियोजना कई बड़े उद्यमियों को निराश करके दी गयी है। इस परियोजना को किसी कंपनी के सुपुर्द करने का फैसला करने के लिए सरकार ने आ साल गंवाये हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदे औद्योगिक विकास निगम ने उक्त परियोजना के लिए देश के १६ बड़े व्यापारिक घरानों से ८०-८ के दौरान प्रार्थना-पत्र मांगे थे। जिन नामीगिरामी घरानों ने इस परियोजना को हासिल करने के लिए प्रयास किया, उनमे बिड़ला, थापर तथा अभय ओसवाल के नाम प्रमुख हैं। किंतु जब आ वर्षों के बाद सलेमपुर परियोजना सिहानि घराने के खाते में गयी, तो देश के उद्यमी घरानों में तहलका मच गया। देश की प्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिक 'बिजनेस इंडिया' ने तो इस समाचार पर आवर कथा तक बना डाली। सलेमपुर परियोजना के साथ ही स्ट्रा प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश में ही प्रतिवर्ष ६०,००० टन एलएबी बनाने के लि लाइसेंस दिया गया तथा विजयपत सिहानिया को रेमण्ड सिंथेटिक्स को पालियस्टर यार्न बनाने की परियोंजना दी गयी। ऐसे में किसी का यह सोचना वाजिब है कि तीनों परिवारों ने परस्पर-सहयोग का समझौता करके ही इस तरह की परियोजना हासिल कीं तथा परियोजनाएं बांटनेवालों ने भी परस्पर-सहयोग को ही लक्ष्य बनाकर एक ही घराने को तीनों परियोजनाएं थमा दीं।

साथ ही, सिहानिया घराने के नौजवान सदस्य रामपति, यदुपति, हर्षपति, अजयपत तथा गौतम सिहानिया भी व्यापार में शामिल हो गये हैं। जाहिर है, नये खून के प्रवेश से व्यापार तथा उद्योग को नये आयाम मिलने की संभावना मजबूत हुई है। ऐसे में यदि तीनों परिवार सूझ-बूझ तथा परस्पर सहयोग की बात को सामने रखते हुए काम करेंगे, तो निस्संदेह इस घराने का भविष्य उज्ज्वल है, किंतु यदि तीन नयी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राप्त करने के बाद भी तीनों परिवारों में आपसी सहयोग का अभाव रहा, तो इस घराने का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा।

—अर्थ विश्ले

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

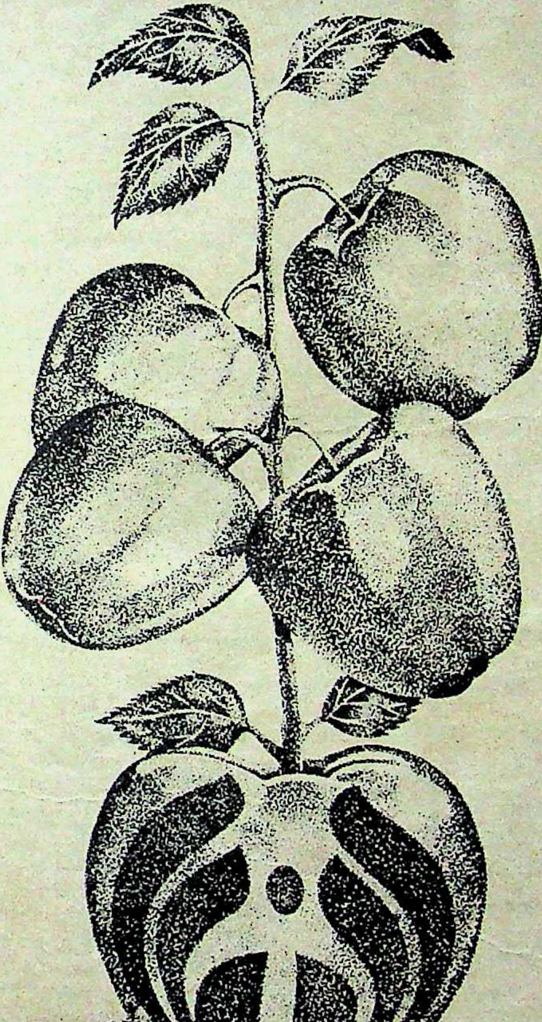

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टावर, कफ़ परेड, कोलाबा, बम्बई 400 005.

Sobhagya-B/89 HN

आगामी चुनाव

नौजवान किसको वोट देंगे?

आगामी चुनाव में ६ करोड़ ऐसे नौजवान मतदान करेंगे, जिनकी उम्र १८ से २० वर्ष के बीच होगी। इनके अतिरिक्त २१ से २५ वर्ष के बीच की आयु के लगभग ९ करोड़ मतदाता भी पहली दफा मतदान में भाग लेंगे।

भारत के कुल ४३ करोड़ मतदाताओं में उपर्युक्त १५ करोड़ युवा मतदाताओं का होना काफी महत्वपूर्ण है। बहुत संभावना है कि ये सब-के-सब वोट डालें, दूसरे इनका उत्साह और इनकी वाचालता उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जो तटस्थ हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि किसी नेता के व्यक्तिगत करिश्मे, ईमानदारी व भ्रष्टाचार, जाति, गरीबी और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बहरहाल, इस मतदाता समूह के रुख को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि चुनाव पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा।

इन नये मतदाताओं को ५४२ निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर देखें, तो लोकसभा के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी संख्या २.७५ लाख बैठती है। यानी हर निर्वाचन क्षेत्र में एक तिहाई नये मतदाता हैं। आमतौर पर लोकसभा का एक स्थान ३३ से ३७ प्रतिशत मतों से जीता जाता है। इसका मतलब है कि अकेले नये मतदाताओं का समूह किसी को भी अपने बलबूते पर जिताकर लोकसभा में भेज सकता है। लेकिन बड़ों की तरह ही इन मतदाताओं के सोच, रुझान और प्राथमिकताओं में भी समानता नहीं है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह नया मतदाता अगले चुनाव में क्या कहर ढायेगा। हालांकि काडर-आधारित वामपंथी दल और आरएसएस की वजह से भाजपा कुछ हद तक मजे में है।

ये नये मतदाता सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों और उनके नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं? ईमानदारी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ये कोई अहमियत देते हैं या नहीं? ये किसको मत देंगे और क्यों? ऐसे अनेक सवाल हैं जो राजनीतिक दलों और प्रेक्षकों के सामने खड़े हैं।

ऐसे अनेक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए हमने जनमत सर्वेक्षण करवाया है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगरों और हैदराबाद तथा पटना जैसे शहरों के १८ से २० वर्ष के नये मतदाताओं के सर्वेक्षण का कार्य हमने इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो (आईएमआरबी) को सौंपा था। इसके अतिरिक्त कुछ चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवान मतदाताओं का सर्वेक्षण हमने स्वयं अपनी 'माया' टीम के जरिये करवाया है। आईएमआरबी का सर्वेक्षण अगस्त १९८९ के पहले पखवारे में संपन्न हुआ है और 'माया' की टीम ने १५ सितंबर, १९८९ तक सर्वेक्षण किया है। यह कहना मुश्किल है कि चुनाव तक इन मतदाताओं का रुख अपरिवर्तित रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ सांसद ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी कुछ ऐसी ही बात कही थी, "हमारे पक्ष में आये जनमत सर्वेक्षण के नतीजे हमारी जीत की गारंटी नहीं हैं।" जाहिर है नौजवानों को हताश और आक्रामक होने में ज्यादा समय नहीं लगता। उनके बारे में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। जनमत सर्वेक्षक ज्यादा-से-ज्यादा संकेत कर सकते हैं, वे भविष्यवक्ता नहीं हैं। प्रस्तुत है, आईएमआरबी का सर्वेक्षण और विश्लेषण:

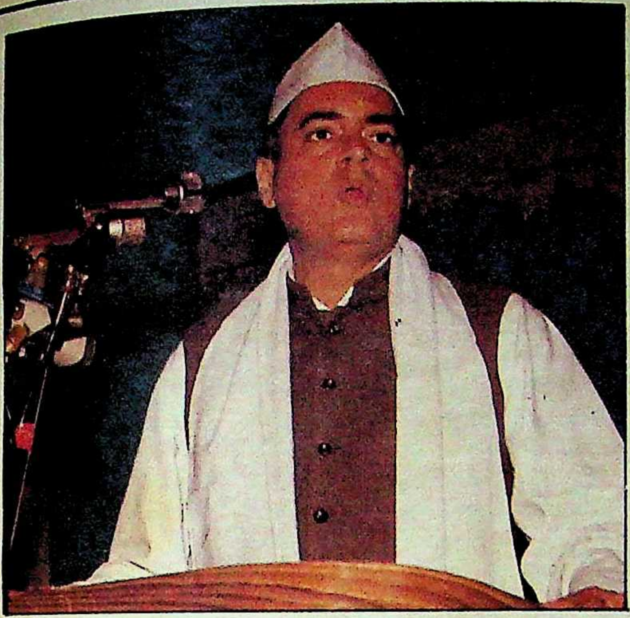

आईएमआरबी

जनमत सर्वेक्षण

कांग्रेस का सिक्का बुलंद

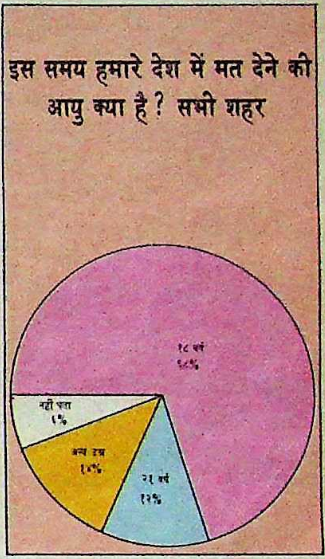

इस समय हमारे देश में मत देने की आयु क्या है ? सभी शहर

शोध कार्यविधि

केंद्र

चार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए चार महानगरों—बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास—को आधार बनाया गया। इसके साथ छोटे नगरों की नुमाइंदगी के लिए हैदराबाद और पटना को भी शामिल किया गया, जो क्रमश: विपक्ष और कांग्रेस के शासन के अंतर्गत हैं।

शोध तकनीक

शोध में नुक्कड़ साक्षात्कार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। द्वार-द्वार साक्षात्कार के बजाय नुक्कड़ साक्षात्कार की तकनीक को इसलिए तरजीह दी गयी, क्योंकि 'आईएमआरबी' का यह तजुर्बा रहा है कि इस विधि से उत्तरदाताओं में झिझक कम होती है और वे अपनी राय बेबाकी से देते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि इससे पहचाने जाने का कोई डर नहीं होता और उत्तरदाता की गुमनामी बरकरार रखी जाती है।

नमूने

१. सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक शहर में मौजूद प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के पांच से छह प्रमुख चौराहों को चुना गया। साक्षात्कार निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर किया गया। इन प्रश्नों को रेखाचित्रों के साथ दिया गया है।

२. चुने गये चौराहों में कार्यालयी या व्यापारिक क्षेत्र, बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के चौराहे सम्मिलित किये गये।

३. कालेज या विश्वविद्यालय के आस-पास का कोई चौराहा नहीं चुना गया। यह इसलिए किया गया, ताकि नमूनों में विद्यार्थियों की भरमार न हो। एक चौराहे पर १५ से ज्यादा उत्तरदाता नहीं चुने गये।

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

व्यवसाय	बंबई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास	हैदराबाद	पटना	कुल
आधार	२४२ %	२१६ %	२०० %	२१० %	२४४ %	२०० %	१३१२ %
विद्यार्थी	५१	६५	६२	४८	५९	८३	६१
बेरोजगार	९	१३	११	२२	२०	९	१४
कुशल/अकुशल श्रमिक	२१	१०	१४	१५	१६	४	१४
क्लर्क/विक्रेता	८	९	६	१२	३	१	६
व्यापारी/दुकानदार	१०	२	४	२	३	३	४
पेशेवर/एक्जीक्यूटिव	१	२	३	१	—	—	१

राजीव गांधी की छवि

कार्य का मूल्यांकन

उत्तरदाताओं से पूछा गया था कि उनकी राय में राजीव गांधी का पिछले साढ़े चार साल का प्रधानमंत्री के रूप में कार्य 'अच्छा' रहा है या 'खराब'? कुल उत्तरदाताओं में से ७० प्रतिशत ने उनका कार्य अच्छा बताया: (देखिए रेखाचित्र/तालिका एक)

प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के काम को आप कैसा मानते हैं?—सभी शहरों में

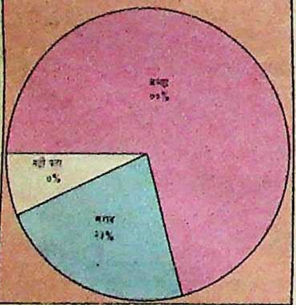

राजधानी दिल्ली में ७८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजीव गांधी का कार्य 'अच्छा' माना। रोचक तथ्य यह है कि हैदराबाद में भी ठीक इतने ही प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजीव गांधी के कार्य को 'अच्छा' माना, जबकि वहां तेलुगूदेशम का शासन है। यहां तक कि वाममोर्चाशासित कलकत्ता में ७५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजीव गांधी के कार्य को 'अच्छा' बताया।

इसकी तुलना में बंबई और पटना में क्रमश: ६३ प्रतिशत और ६९ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही राजीव गांधी का कार्य अच्छा बताया, जबकि दोनों जगह कांग्रेस-इ का शासन है। राजीव गांधी के कार्य को 'अच्छा' बतानेवालों का सर्वाधिक कम प्रतिशत (५७) मद्रास में रहा। वास्तव में बंबई और मद्रास में एक तिहाई या उससे थोड़े अधिक उत्तरदाताओं ने ही राजीव गांधी के कार्य को 'खराब' माना, जबकि क्रमश: चार और सात प्रतिशत ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। उत्तरदाताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किये गये राजीव गांधी के कार्य के मूल्यांकन में ज्यादा फर्क नहीं है। यद्यपि राजीव गांधी के कार्य को 'अच्छा' बतानेवालों में शिक्षित उत्तरदाताओं (विद्यार्थी और मैट्रिक या उससे अधिक) का प्रतिशत थोड़ा कम है। (देखिए निम्नांकित तालिका)।

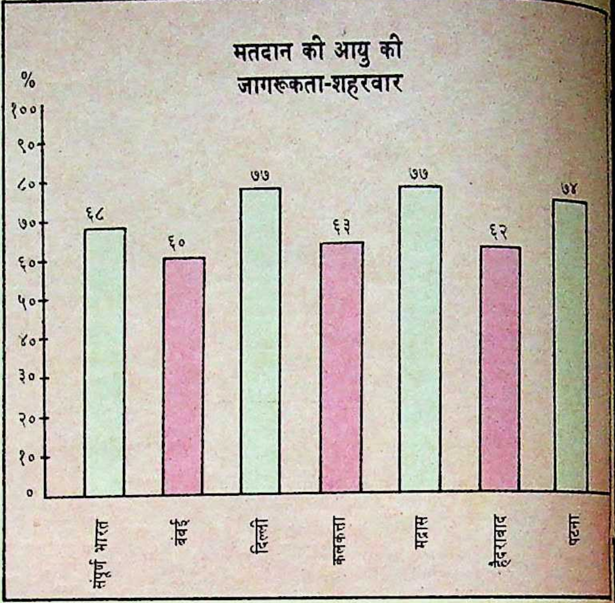
मतदान की आयु की जागरूकता-शहरवार

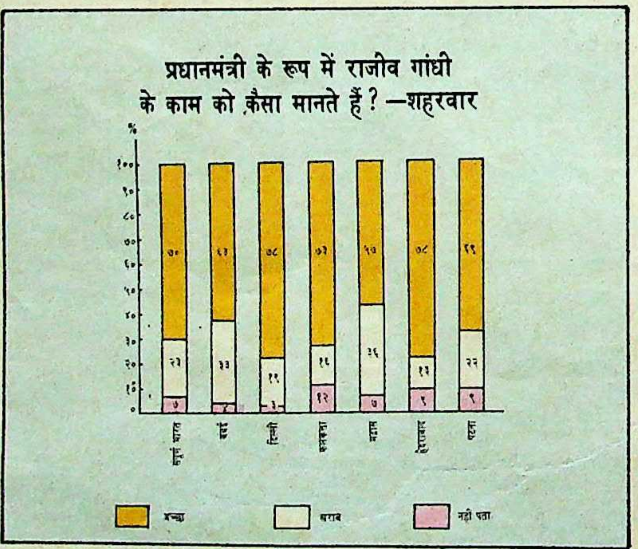
प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के काम को कैसा मानते हैं?—शहरवार

तालिका एक

	कुल	पुरुष	महिला	विद्यार्थी	अन्य	मैट्रिक के नीचे	मैट्रिक – ऊपर
आधार	१३१२ %	६६७ %	६४५ %	८०० %	५१२ %	३०२ %	१००२ %
अच्छा	७०	६९	७०	६८	७१	७५	६८
खराब	२३	२६	२१	२५	२०	१४	२६
नहीं पता	७	५	९	७	९	११	६

भ्रष्ट बनाम ईमानदार का बोध

उत्तरदाता राजीव गांधी को भ्रष्ट मानते हैं या नहीं, यह जानने के लिए परोक्ष प्रश्न पूछा गया। इसका कारण यह था कि हो सकता है, सीधे प्रश्न का वे स्पष्ट उत्तर न दें। अतः उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे विपक्ष के इस आरोप से सहमत हैं या असहमत कि राजीव गांधी भ्रष्ट राजनेता हैं? उनके उत्तर निम्नांकित रेखाचित्र से जाहिर हैं।

विपक्ष का आरोप है कि राजीव गांधी भ्रष्ट राजनेता हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? —सभी शहरों में

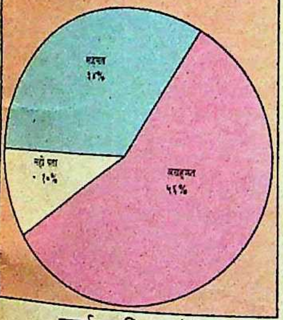

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने विपक्ष के आरोप से असहमति प्रकट की। राजधानी दिल्ली में राजीव गांधी को फिर से सर्वाधिक समर्थन मिला। यहां ६८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस कथन को नहीं माना कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं। केवल मद्रास ऐसा शहर है, जहां अधिसंख्य उत्तरदाताओं ने यह माना कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं। इसके बाद बंबई का स्थान आता है, जहां ४३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजीव गांधी को भ्रष्ट माना है। नीचे दी गयी तालिका (दो) से स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओं की राय में ज्यादा अंतर नहीं है।

यहां पर उल्लेखनीय है कि जिन उत्तरदाताओं ने 'नहीं पता' (इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि उन्होंने राय नहीं बनायी थी) कहा, उनका प्रतिशत महिलाओं (१२ प्रतिशत), गैरविद्यार्थी उत्तरदाताओं (१३ प्रतिशत) और मैट्रिक से कम पढ़े उत्तरदाताओं में अपेक्षाकृत अधिक रहा है।

मतदान की आयु २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष करने का श्रेय किस नेता को जाता है?—सभी शहरों में

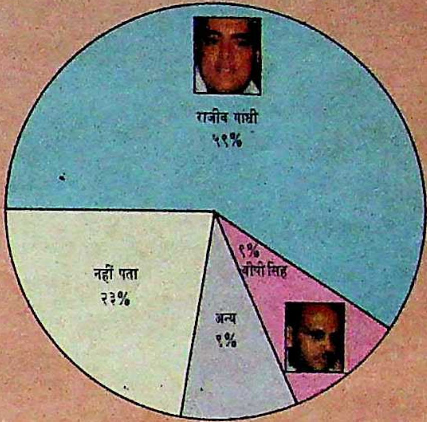

विपक्ष का आरोप है कि राजीव गांधी भ्रष्ट राजनेता हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? —शहरवार

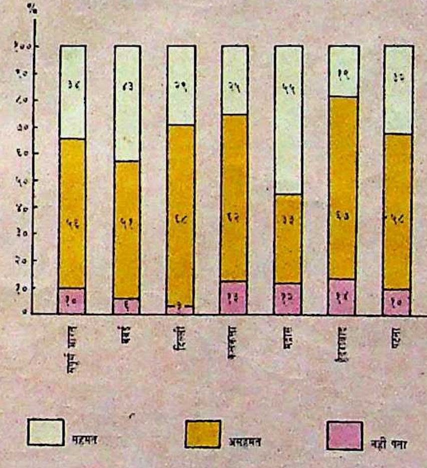

कुछ शहरों में उत्तरदाताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के विचारों में काफी अंतर रहा है। जैसे दिल्ली में ७५ प्रतिशत महिला उत्तरदाता आरोप से असहमत हैं, जबकि वहां पुरुषों में ६० प्रतिशत ही असहमत हैं। कलकत्ता, हैदराबाद और पटना में विद्यार्थी समूह और गैरविद्यार्थी समूह के उत्तरदाताओं की राय में अंतर है। जैसे कलकत्ता के ६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तरदाता विपक्ष के इस आरोप से असहमत हैं कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं, जबकि गैरविद्यार्थियों का प्रतिशत ५५ है। इस संदर्भ में हैदराबाद और पटना में क्रमशः ६३ प्रतिशत (विद्यार्थी) के मुकाबले ७२ प्रतिशत (गैर विद्यार्थी) और ६० प्रतिशत (विद्यार्थी) के मुकाबले ४६ प्रतिशत (गैर विद्यार्थी) रहा है।

तालिका दो

	कुल	पुरुष	महिला	विद्यार्थी	अन्य	मैट्रिक से नीचे	मैट्रिक – ऊपर
आधार	१३१२	६६७	६४५	८००	५१२	३०२	१००२
	%	%	%	%	%	%	%
सहमत	३४	३७	३१	३५	३२	२७	३६
असहमत	५६	५६	५७	५७	५५	५५	५७
नहीं पता	१०	७	१२	८	१३	१७	८

सीएजी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया

राजीव गांधी का इस्तीफा

उत्तरदाताओं की इस मुद्दे पर राय जानी गयी थी कि बोफोर्स के संबंध में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट के बाद राजीव गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? उनके उत्तर निम्नांकित रेखाचित्र में प्रदर्शित हैं।

यहां भी आधे से कुछ अधिक—५१ प्रतिशत उत्तरदाताओं की राय थी कि राजीव गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अकेला मद्रास ऐसा नगर है, जहां अधिसंख्य उत्तरदाताओं ने माना कि राजीव गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था।

इस प्रश्न के उत्तर में 'नहीं पता' कहनेवालों की संख्या काफी अधिक थी—१८ प्रतिशत। 'नहीं पता' कहनेवालों की संख्या कलकत्ता में सर्वाधिक थी—३३ प्रतिशत और बंबई में न्यूनतम—८ प्रतिशत। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में २० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी 'नहीं पता' कहा। इसके दो कारण हो सकते हैं:

बोफोर्स पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद राजीव गांधी को क्या करना चाहिए था? —सभी शहरों में

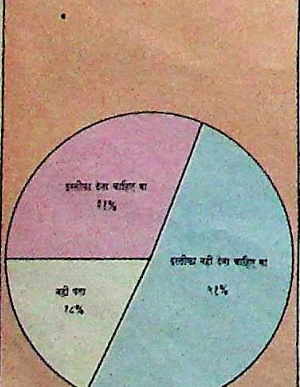

(क) ये उत्तरदाता बोफोर्स पर सीएजी की रिपोर्ट और उसके परिणामों से अनजान थे।

(ख) यद्यपि वे इससे जुड़े मुद्दों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी राय नहीं बनायी थी।

सीएजी की रिपोर्ट के बारे में कम जानकारी होने की ज्यादा संभावना है। इसका कारण यह है कि 'नहीं पता' कहनेवालों में 'गैर-विद्यार्थियों' और 'गैरमैट्रिक' (क्रमशः २६ प्रतिशत और ३८ प्रतिशत) उत्तरदाताओं का प्रतिशत ज्यादा था। जिन लोगों ने उत्तर दिये, उनमें से अधिकांश की राय थी कि राजीव गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।

बोफोर्स पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद राजीव गांधी को क्या करना चाहिए था? —शहरवार

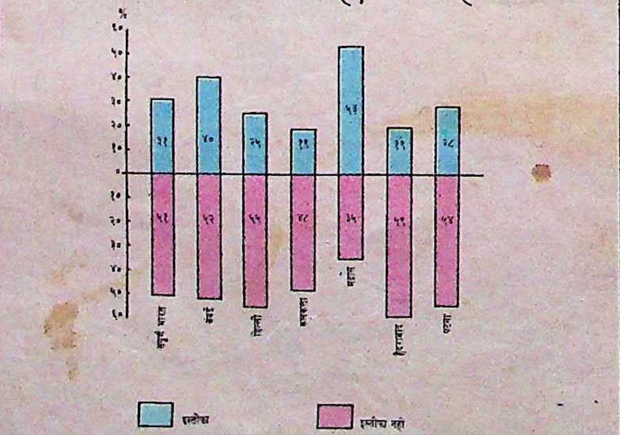

विपक्ष का इस्तीफा

उपर्युक्त प्रश्न के बाद उत्तरदाताओं की इस मुद्दे पर राय जानी गयी कि राजीव गांधी के इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद क्या विपक्ष को विरोधस्वरूप लोकसभा से एक साथ इस्तीफा देना चाहिए था? पूछा गया था कि विपक्ष का यह कदम उचित था या नहीं। उत्तरदाताओं की राय निम्नांकित रेखाचित्र में प्रदर्शित है।

राजीव गांधी के इस्तीफा न देने से विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। क्या आपकी दृष्टि में यह कदम ठीक था? —शहरवार

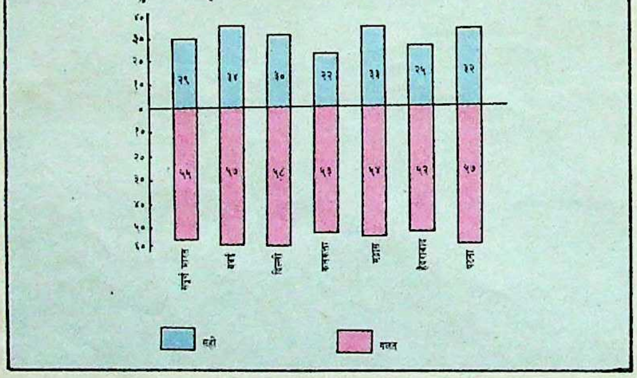

राजीव गांधी के इस्तीफा न देने से विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। क्या आपकी दृष्टि में यह कदम ठीक था? —सभी शहरों में

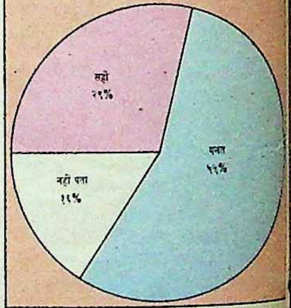

उपर्युक्त रेखाचित्रों से जाहिर है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (५५ प्रतिशत) की राय थी कि विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा देकर सही काम नहीं किया। इस मुद्दे पर भिन्न-भिन्न शहरों के उत्तरदाताओं के विचार में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं था।

एक बार फिर 'नहीं पता' कहनेवाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन राजीव गांधी के इस्तीफे के मुद्दे पर 'नहीं पता' कहनेवालों से थोड़ा कम प्रतिशत था। यहां भी 'नहीं पता' कहनेवालों में ज्यादा गैरविद्यार्थी (२५ प्रति-शत) और गैरमैट्रिक (३३ प्रतिशत) थे।

राजनीतिक दलों की स्थायी सरकार देने की योग्यता

स्थायी केंद्रीय सरकार

यह जानने के लिए कि युवा मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों की क्षमता के बारे में क्या राय रखते

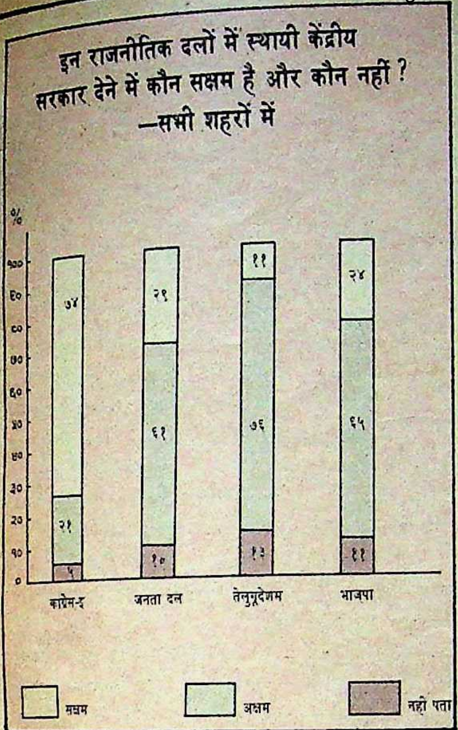

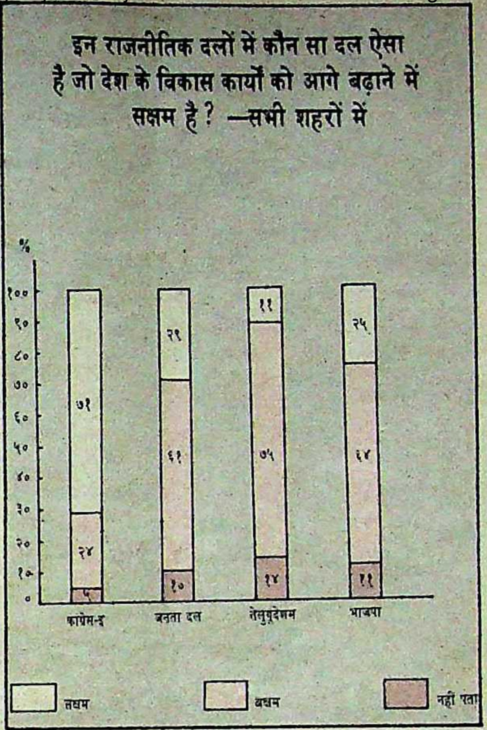

हैं? उत्तरदाताओं को कुछ प्रमुख दलों की एक सूची दी गयी। फिर उनसे पूछा गया कि उनकी राय में कौन दल ऐसा है जो केंद्र में स्थायी सरकार दे सकता है और कौन नहीं? प्राप्त उत्तरों को निम्नांकित रेखाचित्रों में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त रेखाचित्र में कांग्रेस-इ स्पष्ट विजेता के रूप में उभरती है। ७४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि कांग्रेस-इ स्थायी केंद्रीय सरकार देने में सक्षम है। विपक्षी दलों को अपेक्षाकृत बहुत कम प्रतिशत मिला।

मतदान का इरादा

राजनीतिक दल

राजनीतिक पसंद की अंतिम परीक्षा इस बात से होती है कि किस राजनीतिक दल को मत देने की इच्छा है। इसके लिए उत्तरदाताओं के सामने एक कल्पित स्थिति रखी गयी—'अगर आज लोकसभा का चुनाव हो'—इसके बाद उनसे पूछा गया कि वे उस दल का नाम बतायें, जिसको वे मत देना चाहेंगे। यह ध्यान में रखने की बात है कि यह केवल 'नये मतदाता' का इरादा है। यह जरूरी नहीं कि यह सार्वदेशिक राय हो। इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार मिले :

अधिसंख्य—६२ प्रतिशत—कांग्रेस-इ के पक्ष में थे। यह स्थिति सभी शहरों में थी। कुल मिलाकर जनता दल काफी बाद में दूसरे स्थान (१५ प्रतिशत) पर आता है और भाजपा तीसरे स्थान (१० प्रतिशत) पर।

रोचक बात यह है कि एक प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे किसी को मत नहीं देंगे। यह या

तालिका तीन

	कुल	पुरुष	महिला	विद्यार्थी	अन्य	मैट्रिक से नीचे	मैट्रिक — ऊपर
आधार	१३१२	६६७	६४५	८००	५१२	३०२	१००२
	%	%	%	%	%	%	%
कांग्रेस-इ	६२	५८	६५	६०	६५	६५	६०
भाजपा	१०	११	८	१०	९	७	११
जनता दल	१५	१६	१२	१६	१४	१३	१६
तेलुगूदेशम	४	४	४	४	४	६	४
अन्य	६	५	६	६	५	६	६
नहीं पता	२	१	२	१	२	२	१
वोट नहीं देंगे	१	१	३	३	१	१	२

तो मोहभंग का सूचक है या राष्ट्रीय राजनीति में रुचि न होने का।

कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों को खास शहरों में अच्छे अनुपात में सकारात्मक मत मिले हैं। उदाहरण के लिए :

१. ***जनता दल:*** मद्रास में ३४ प्रतिशत और पटना में २२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि इसे वोट देंगे।

२. ***भाजपा:*** बंबई और दिल्ली के १८-१८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे वोट देने के लिए कहा।

३. ***कलकत्ता*** में २३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सूची में वर्णित दलों के अतिरिक्त किसी दल को मत देंगे। ज्यादातर लोगों ने इस अन्य दल का नाम सीपीएम बताया। कुछ ने सीपीआई और वाम मोर्चा का नाम लिया।

यह आश्चर्य की बात है कि हैदराबाद में केवल १७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे तेलुगूदेशम को मत देंगे। इससे संकेत मिलता है कि तेलुगूदेशम सत्तारूढ़ दल होते हुए भी युवा मतदाताओं में लोकप्रिय नहीं है। यही बात कलकत्ता में वाममोर्चा के लिए कही जा सकती है। मतदान की पसंद कमोबेश सभी श्रेणियों के उत्तरदाताओं में समान थी, जैसा कि तालिका (तीन) से जाहिर होता है।

यदि लोकसभा के चुनाव आज हों, तो आप किस दल को मत देना चाहेंगे? —सभी शहरों में

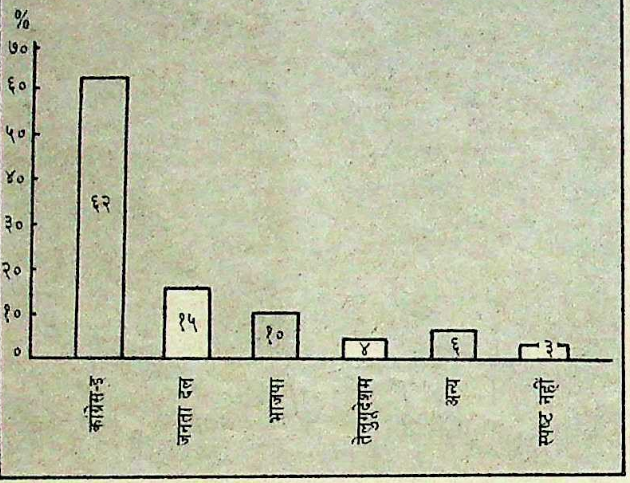

राजनीतिक नेता

राजनीतिक दल के बारे में उत्तरदाताओं की पसंद जान लेने के बाद उनसे प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया। यहां भी राजीव गांधी अन्य विपक्षी राजनेताओं से काफी आगे रहे। निम्नांकित रेखाचित्र इसी का द्योतक है।

इससे जाहिर होता है कि राजीव गांधी को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से ४० प्रतिशत अधिक पसंद किया गया। वैसे सभी विपक्षी नेताओं की स्थिति काफी खराब रही।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कांग्रेस-इ को वोट देनेवालों का प्रतिशत राजीव गांधी को वोट देने वालों से ज्यादा था। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस-इ को सत्तारूढ़ दल के रूप में पसंद करनेवाले ज्यादा थे, जबकि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करने वाले कम थे।

राजीव गांधी को पसंद करनेवालों का प्रतिशत हैदराबाद और कलकत्ता में सर्वाधिक था—क्रमशः ७३ प्रतिशत और ६३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे राजीव गांधी को वोट देना चाहेंगे। यह आश्चर्य की बात इसलिए है, क्योंकि इन शहरों का झुकाव विपक्ष की ओर माना जाता है।

वीपी सिंह को मद्रास, पटना और बंबई में समर्थन मिला। जहां क्रमशः २२, २१ और १६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे उनको वोट देना चाहेंगे। राजीव गांधी के बारे में भिन्न-भिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओं की पसंद कुछ हद तक अलग-अलग थी। जिन्होंने ज्यादा पसंद किया उनमें 'गैर विद्यार्थी' (६३ प्रतिशत), 'गैर मैट्रिक' (६६ प्रतिशत) और महिलाएं (६१ प्रतिशत) थीं।

◆

प्रधानमंत्री के लिए आप किस नेता को मत देना चाहेंगे? —सभी शहरों में

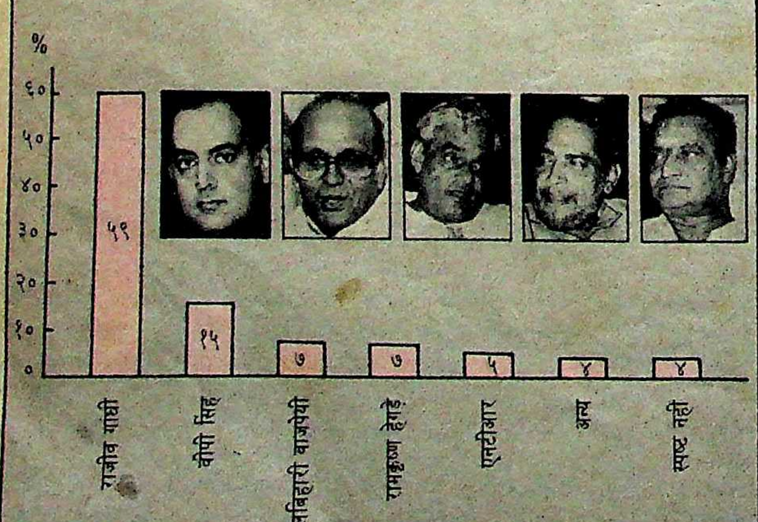

प्रधानमंत्री के लिए आप किस नेता को मत देना चाहेंगे? —शहरवार

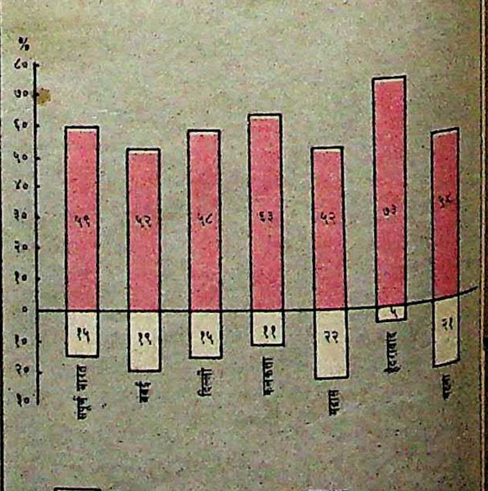

वीपी सिंह

माया-सर्वेक्षण : ग्रामीण क्षेत्र के युवा मतदाता

टक्कर बराबरी की है

राजीव गांधी

१८ से २० वर्ष की वय किशोरावस्था और युवावस्था का एक प्रकार से संधिकाल होता है और यह वह उम्र है, जिसमें व्यक्ति की स्थिति सर्वाधिक विचित्र रहती है। मसें भीगने लगती हैं और मूंछ-दाढ़ी की हलकी सी झलक चेहरे पर उभर आती है। न वह बच्चा नजर आता है और न ही युवा। जब वह खुद को युवा मानकर कोई राय व्यक्त करता है, तो उसे बचकाना माना जाता है, लेकिन जब वह बालकों के समान आचरण करता है, तो उसे यह सुनकर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है कि अब वह बड़ा हो गया है। परिवारों और मोहल्लों में भले ही इस आयुवर्ग के युवाओं के विचारों पर ध्यान न दिया जाये, लेकिन नौवीं लोकसभा के लिए होनेवाले आम चुनाव में इस आयुवर्ग के मतदाता दिल्ली का तख्त पलट सकते हैं। इस आयुवर्ग के छह करोड़ मतदाताओं में से करीब पौने दो करोड़ युवा शहरों में रहते हैं और सवा चार करोड़ गांवों में। यह नया युवा मतदाता क्या सोचता है? शहरी क्षेत्र के युवाओं की राय जानने का काम 'माया' ने सर्वेक्षण विशेषज्ञ संस्था आईएमआरबी को सौंपा था, जिसने देश के चार प्रमुख बड़े नगरों—दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बंबई तथा दो प्रदेश राजधानियों पटना और हैदराबाद शहर के नये युवा मतदाताओं का सर्वेक्षण किया है। 'माया' ने पाठकों के सामने युवा जनमानस की पूरी तस्वीर पेश करने के इरादे से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का भी विशेष सर्वेक्षण कराया। इसके लिए देश के इन दस शहरों के ग्रामीण इलाकों को चुना गया—कलकत्ता, जयपुर, बिजनौर, उज्जैन, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, देवरिया-गोरखपुर और पटना। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि 'माया' की सर्वेक्षक टीम इन शहरों से १० से ४० किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क से दूर के गांवों में जाकर १८ से २० वर्ष की वय के युवक और युवतियों की राय एक निर्धारित सर्वे-फार्म के जरिए प्राप्त करे। इनमें से अधिकांश युवा खेती-किसानी-मजदूरी और व्यापार से जुड़े हैं, तो अनेक युवा नजदीक के शहर में पढ़ने या कोई छोटा-मोटा काम करने जाते हैं और शाम को वापस गाव चले जाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण युवाओं की राय जानने के लिए जयपुर के उत्तर पूर्व में ४० किमी दूर स्थित रामगढ़, रायावाल, थली व आंधी तथा अजमेर रोड पर जयपुर से ३५ किलोमीटर दूर स्थित महापुरा, बड़के बालाजी, खटवाड़ा और माटरकोटा गांवों को चुना गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद के आसपास के गांवों का सर्वेक्षण किया गया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के रामपुर बकली गाव तक 'माया' की टीम पहुंची। इस तरह 'माया' ने ३५९० ग्रामीण युवा मतदाताओं का सर्वे किया।

सर्वेक्षण फार्म में आठ सवाल इस प्रकार के रखे गये थे; जिससे यह स्पष्ट रूप से उभर कर आ सके कि राजीव गांधी और उनकी सरकार, राजनीतिक दल और सुयोग्य प्रधानमंत्री की पसंद, मताधिकार किसके कारण मिला तथा आम चुनाव में किस पार्टी की जीत की संभावना है, आदि के मामले में देश के शहरी युवाओं के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के युवा मतदाता क्या राय रखते हैं? और वस्तुतः 'माया' ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि मताधिकार किसके कारण मिला?—इस सवाल को छोड़कर बाकी हर मामले में देश के शहरी युवाओं के मुकाबले ग्रामीण युवाओं की राय में चौंकानेवाला अंतर है?

सर्वेक्षण निकष : आईएमआरबी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जहां शहरी युवा मतदाता कांग्रेस और राजीव गांधी की लोकप्रियता को बुलंदी पर स्थापित हुआ मान रहा है, वहीं 'माया' टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के निकष बताते हैं कि राजीव गांधी के लिए आगामी आमचुनाव जीतना उतना आसान नहीं है जितना कि शहरी युवा मतदाता की राय से आभासित होता है। जहां ७० प्रतिशत शहरी युवा राजीव गांधी के साढ़े चार साल के शासन को अच्छा बताते हैं वहीं ५३.८ प्रतिशत ग्रामीण युवा यह मानते हैं कि राजीव गांधी का साढ़े चार साल का शासन अच्छा नहीं रहा। शहरी युवाओं में राजीव गांधी को ईमानदार माननेवाले दिल्ली में जहां ६८ प्रतिशत हैं, वहीं दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के सिर्फ ४४.२ प्रतिशत ऐसा मानते हैं, जबकि इसके विपरीत राय रखनेवाले कुल ग्रामीण युवाओं का प्रतिशत ५४.२ है। ६२ प्रतिशत शहरी युवा मतदाता कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन ग्रामीण युवाओं में कांग्रेस और विपक्ष को पसंद करनेवालों की संख्या बराबर (४८.६-४८.६%) है। राजीव सरकार को ईमानदार और उनके शासन को अच्छा माननेवालों में सिर्फ कलकत्ता और जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा मतदाता बहुसंख्या में हैं और इन दो शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुसंख्य युवा मतदाता कांग्रेस को पसंद करते हैं, उसे ही वोट देंगे और उसी की जीत की संभावना व्यक्त करते हैं। सुयोग्य प्रधानमंत्री के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वाधिक ४६.९ प्रतिशत युवा मतदाता राजीव गांधी को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि वीपी सिंह को सुयोग्य प्रधानमंत्री माननेवालों का प्रतिशत २७.४ है। अर्थात् राजीव गांधी के पक्ष में वीपी सिंह के मुकाबले सिर्फ २० प्रतिशत का अंतर है, जबकि आईएमआरबी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार शहरी युवाओं में यह अंतर ४० प्रतिशत है। वहां ५९ प्रतिशत राजीव गांधी को तथा १५ प्रतिशत वीपी सिंह को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता गांव और शहरों में एक समान है। १५ प्रतिशत शहरी युवा और १४.८ प्रतिशत ग्रामीण युवा उन्हें योग्य प्रधानमंत्री मानता है। ग्रामीण अंचल के ५६.७ प्रतिशत युवा मतदाता ईमानदारी को तरजीह देते हैं, ५५.६ प्रतिशत विपक्ष की स्थिति को मजबूत बताते हैं और ५३.५ प्रतिशत विपक्ष की विजय में आस्था व्यक्त करते हैं। ३५९० ग्रामीण युवा मतदाताओं में युवा महिलाओं ने भी अपनी राय व्यक्त की है। जहां विपक्ष को वोट देने और विपक्ष की विजय में विश्वास व्यक्त करनेवाली ग्रामीण युवा महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः ४६.४ और ४४.१ है, वहीं कांग्रेस को वोट देने और उसकी विजय में आस्था व्यक्त करनेवाली ग्रामीण युवा महिलाओं का प्रतिशत ५०-५० है। इस सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस और विपक्ष के पक्षधर मुकाबले की संख्या में हैं और आगामी चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी दंगल मुकाबले की ताकत के साथ होगा। यहां प्रस्तुत हैं, प्रश्नानुसार, सर्वेक्षण परिणाम:

क्या राजीव गांधी की सरकार ईमानदार है?

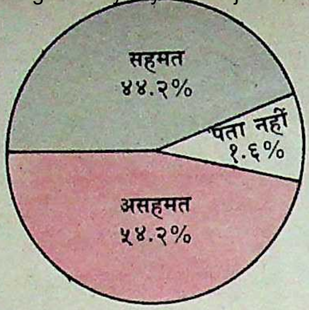

देश के दस प्रमुख शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के ३५६० नये मतदाताओं (१८-२० वर्ष) में से ५४.२ प्रतिशत अर्थात बहुमत यह मानता है कि राजीव की सरकार ईमानदार नहीं है। सिर्फ ४४.२ प्रतिशत युवक इसके विपरीत राय रखते हैं। कलकत्ता, जयपुर और मेरठ के बहुसंख्य ग्रामीण युवक क्रमशः ६६.६, ७०, ७३.३ प्रतिशत राजीव गांधी की सरकार को ईमानदार मानते हैं, जबकि उसे ईमानदार न माननेवालों में उज्जैन (५६.९%), लखनऊ (५९.२%), इलाहाबाद (६६.९%), देवरिया-गोरखपुर (८५.७%), भोपाल (५२.२%) और पटना (५६.९%) के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुसंख्य युवक शामिल हैं। राजीव सरकार को ईमानदार माननेवालों में दिल्ली के ग्रामीण युवकों का प्रतिशत ४९.२ रहा।

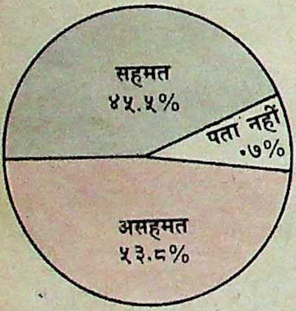

क्या राजीव का शासन अच्छा रहा?

कुल ३५९० ग्रामीण युवा उत्तरदाताओं में से ५३.८ प्रतिशत अर्थात बहुसंख्य ऐसा नहीं मानते कि राजीव गांधी का शासन अच्छा रहा है। केवल कलकत्ता (६२.९%), जयपुर (७३.३%) और बिजनौर (७०%) के बहुसंख्य ग्रामीण युवक राजीव शासन को अच्छा मानते हैं, जबकि उसे अच्छा न माननेवालों में उज्जैन (६०.३%), दिल्ली (५४.४), लखनऊ (५१.३%), इलाहाबाद (५९.७%), देवरिया-गोरखपुर (८५.७%) भोपाल (६०.९%) व पटना (६१.१%) के बहुसंख्य ग्रामीण युवक शामिल हैं।

आपको मताधिकार किसके कारण मिला?

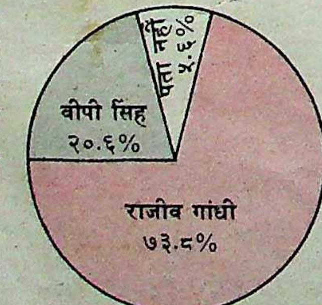

ग्रामीण युवकों में से ७३.८ प्रतिशत की स्पष्ट मान्यता है कि उन्हें राजीव गांधी के कारण मताधिकार प्राप्त हुआ। इस सवाल के जवाब में ग्रामीण युवक, शहरी युवकों के मुकाबले कहीं अधिक जागरूक साबित हुए। आईएमआरबी द्वारा शहरी युवकों से पूछे गये इस सवाल के उत्तर में जहां २३ प्रतिशत यह नहीं जानते थे कि उन्हें मताधिकार किसके कारण मिला, वहीं यह न जाननेवाले ग्रामीण युवकों का प्रतिशत मात्र ५.६ रहा। इलाहाबाद, लखनऊ, बिजनौर और पटना में तो राजीव गांधी को इसका श्रेय देनेवालों का प्रतिशत क्रमशः ७३.३, ८८.१, ८६.७ और ९०.३ रहा। देवरिया-गोरखपुर के ग्रामीण युवक इसके लिए राजीव गांधी और वीपी सिंह को समान रूप से श्रेय देते हैं।

आप किसको वोट देंगे?

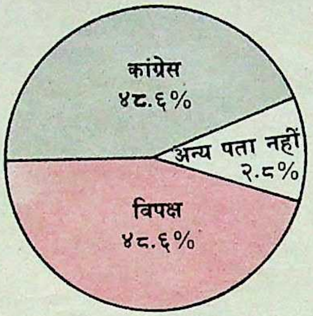

यह मात्र संयोग ही है कि देश के दस शहरों के ३५९० ग्रामीण युवकों में से कांग्रेस और विपक्ष को वोट देने का इरादा जाहिर करनेवालों की संख्या बराबर-बराबर रही है। १७४५ मतदाता (४८.६ प्रतिशत) पक्ष में हैं, तो इतने ही विपक्ष में। केवल १०० ग्रामीण युवकों ने अपनी राय बताने से इनकार किया। कांग्रेस को जिताने का इरादा जाहिर करनेवालों में कलकत्ता (६६.७%), जयपुर (६६.७%), बिजनौर (६०.३%), उज्जैन (६०.३%), लखनऊ (५३.९%) और पटना (५१.४%) के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा शामिल हैं। सर्वाधिक रोचक तथ्य यह है कि आईएमआरबी के सर्वेक्षण के अनुसार जहां दिल्ली के शहरी क्षेत्र के ६८ प्रतिशत युवा उत्तरदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने का इरादा जाहिर किया वहीं 'माया' के सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली-ग्रामीण क्षेत्र ४३.१ प्रतिशत युवा ही कांग्रेस के पक्षधर थे, जबकि ४९.२% ग्रामीण युवा (दिल्ली) विपक्ष के प्रति प्रतिबद्ध पाये गये। कलकत्ता के शहरी क्षेत्र के ५९ प्रतिशत युवा कांग्रेस के साथ हैं (आईएमआरबी), तो ग्रामीण क्षेत्र के ६६.७ प्रतिशत युवा कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के पक्षधर शहरी युवा जहां पटना में ६२ प्रतिशत हैं (आईएमआरबी), वहीं पटना के ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस के पक्षधर युवाओं का प्रतिशत घटकर ५१.४ रह गया है। दिल्ली के साथ ही, देवरिया-गोरखपुर, इलाहाबाद और भोपाल के बहुसंख्य ग्रामीण युवा कांग्रेस-विरोधी हैं। यहां के क्रमशः ७६.२, ६१.१ और ६३.१ प्रतिशत ग्रामीण युवाओं ने विपक्ष को वोट देने की इच्छा जाहिर की है।

सुयोग्य प्रधानमंत्री कौन है?

'माया' ने दस शहरों के ग्रामीण युवकों से देश के आठ दिग्गज नेताओं (राजीव गांधी, वीपी सिंह, रामकृष्ण हेगड़े, अजीत सिंह, देवीलाल, एनटीआर, चंद्रशेखर और वाजपेयी) के नामों में से योग्यतम प्रधानमंत्री के उपयुक्त नाम की जानकारी चाही थी। इस मतदान में राजीव गांधी को ४६.९, वीपी सिंह को २७.४, हेगड़े को १.९, अजीत सिंह को .८३, देवीलाल को ३.९, एनटीआर को १.४, चंद्रशेखर को १.७ तथा अटल बिहारी वाजपेयी को १४.८ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। राजीव गांधी को दिल्ली के शहरी क्षेत्र के जहां ५८ प्रतिशत, कलकत्ता के ६३ प्रतिशत और पटना के शहरी क्षेत्र के ५४ प्रतिशत युवकों ने आईएमआरबी के सर्वेक्षण के अनुसार योग्यतम प्रधानमंत्री माना है, वहीं 'माया' द्वारा उक्त शहरों के

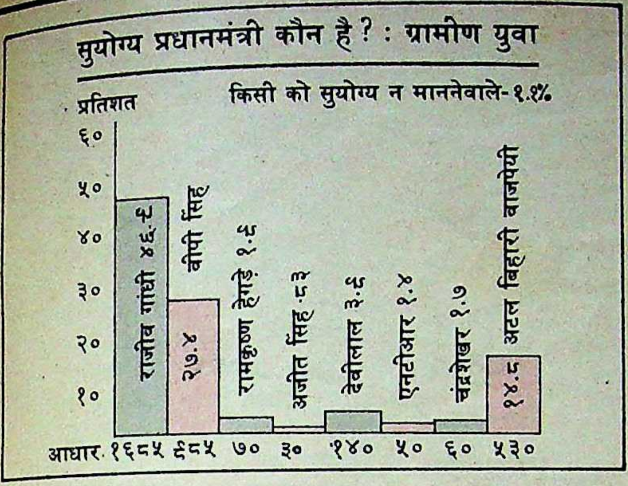
सुयोग्य प्रधानमंत्री कौन है ? : ग्रामीण युवा

आसपास के ग्रामीण इलाकों द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दिल्ली को छोड़कर कोई खास फर्क नहीं है। कलकत्ता ग्रामीण क्षेत्र के ६२.९६ प्रतिशत और पटना-ग्रामीण क्षेत्र के जहां ५२.८ प्रतिशत युवा राजीव गांधी को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानते हैं। वहीं ऐसा माननेवालों में दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के सिर्फ ४४.६ प्रतिशत युवा शामिल हैं। इलाहाबाद में ३६.९ प्रतिशत युवा राजीव गांधी को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानते हैं, तो वहीं वीपी सिंह को सुयोग्य प्रधानमंत्री माननेवालों की संख्या इससे कुछ ही कम ३१.७ प्रतिशत है। रोचक तथ्य यह है कि भोपाल में राजीव गांधी को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानंनेवालों का प्रतिशत सिर्फ २८.२ प्रतिशत है, जबकि भाजपा का गढ़ कहे जाने के बावजूद इस क्षेत्र के ५२.२ प्रतिशत युवा मतदाता वीपी सिंह को सुयोग्य प्रधानमंत्री मानते हैं, वहीं सिर्फ १०.९ प्रतिशत अटल बिहारी वाजपेयी के पक्षधर पाये गये। अटल बिहारी वाजपेयी को सुयोग्य प्रधानमंत्री माननेवाले किसी न किसी संख्या में बिजनौर को छोड़कर अन्य हर शहर में मिले। लोकप्रियता के क्रम में उनका स्थान तीसरा है, यद्यपि उन्हें कुल ३५९० मतदाताओं में से सिर्फ ५३० अर्थात १४.८ प्रतिशत मत मिले।

किसी दल को किस विशेषता के कारण वोट देंगे ?

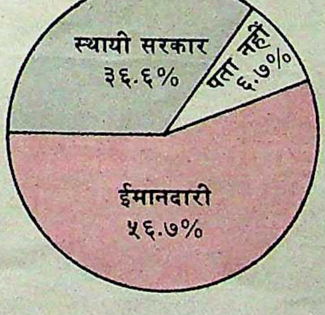

'माया' द्वारा देश के दस शहरों के ग्रामीण क्षेत्र के नये मतदाताओं से यह जानकारी चाही गयी थी कि वे किसी दल को उसके नेताओं की ईमानदारी के कारण वोट देंगे या उनकी स्थायी सरकार देने की क्षमता के कारण—५६.७ प्रतिशत युवा मतदाताओं का कहना था कि वे ईमानदारी को तरजीह देंगे, जबकि स्थायी सरकार देने की क्षमता को पसंद करनेवाले युवकों का प्रतिशत ३६.६ रहा। सिर्फ जयपुर (७३.३%), उज्जैन (४८.३%) और पटना (५६.९%) के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुसंख्य मतदाता स्थायी सरकार के पक्षधर रहे, जबकि ईमानदारी के बहुसंख्य पक्षधर कलकत्ता के ग्रामीण क्षेत्रों में ५३.७०, बिजनौर में ८०, दिल्ली में ६४.६, इलाहाबाद में ५९.३, देवरिया-गोरखपुर में ६६.७ तथा भोपाल में ८२.६ प्रतिशत रहे।

किस दल की स्थिति मजबूत हुई है ?

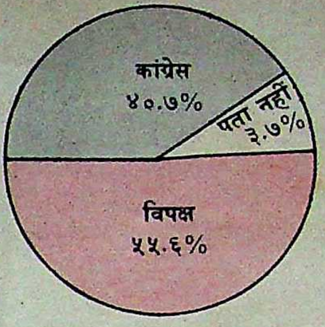

'माया' द्वारा सर्वेक्षित ग्रामीण युवाओं के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि ५५.६ प्रतिशत ग्रामीण युवा मानते हैं कि हाल ही विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि कांग्रेस को मजबूत माननेवालों का प्रतिशत सिर्फ ४०.७ है। कांग्रेस की स्थिति को जिन शहरों के बहुसंख्य ग्रामीण युवा मजबूत मानते हैं, वे शहर हैं—कलकत्ता (५३.७०%), जयपुर (६०%), बिजनौर (६३.३) और उज्जैन (४८.३%) है। दिल्ली के सिर्फ २७.७% ग्रामीण युवा कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ करार देते हैं, जबकि विपक्ष की स्थिति मजबूत माननेवालों का दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत ४९.२ है। लखनऊ के ५२.६, इलाहाबाद के ६३.५, देवरिया-गोरखपुर के ८०.९, भोपाल के ६५.२ और पटना के ६२.५ प्रतिशत ग्रामीण युवा मानते हैं कि पिछले दिनों विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है।

निष्पक्ष चुनाव में जीत किसकी होगी ?

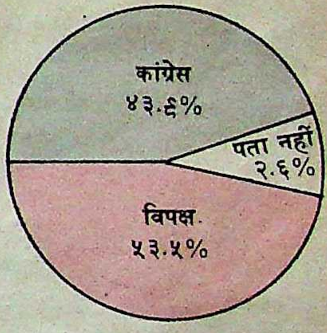

केवल कलकत्ता (६२.९%), जयपुर (६३.३%) और बिजनौर (६३.३%) के ग्रामीण युवक ही निष्पक्ष चुनाव होने पर कांग्रेस की विजय की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन 'माया' द्वारा सर्वेक्षित किये गये दस शहरों के कुल ३५९० मतदाताओं में से बहुसंख्य ५३.५ प्रतिशत ग्रामीण युवक मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने पर कांग्रेस हार जायेगी, जबकि कांग्रेस की विजय में विश्वास व्यक्त करनेवालों का प्रतिशत सिर्फ ४३.९ है। दिल्ली (५०.७%), लखनऊ (५७.९%), इलाहाबाद (६१.४%), देवरिया-गोरखपुर (८०.९%), भोपाल (६३.१%) और पटना (५१.४%) जिले के बहुसंख्य ग्रामीण युवा मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने पर जीत विपक्ष की होगी।

युवा महिलाओं की राय : 'माया' ने देश के दस शहरों के जिन ३५९० युवा मतदाताओं का सर्वेक्षण किया था, उनमें ४२० युवा महिला मतदाता भी थीं। रोचक तथ्य यह है कि कांग्रेस को वोट देने, राजीव गांधी को सुयोग्य प्रधानमंत्री माननेवाली और कांग्रेस की जीत में विश्वास व्यक्त करनेवाली युवा महिलाओं की संख्या (५० प्रतिशत) समान है। जबकि ५५.९ प्रतिशत युवा महिलाओं का कहना है कि राजीव सरकार ईमानदार नहीं है, ५४.८ प्रतिशत मानती हैं कि राजीव सरकार का शासन अच्छा नहीं रहा, ५७.१ प्रतिशत ने ईमानदारी को तरजीह दी है, जबकि ५१.२ प्रतिशत युवा महिलाओं की राय में पिछले चार मास में विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है। अर्थात हर क्षेत्र में टक्कर बराबरी की है।

—आकलन एवं समीक्षा : विनोद मिश्र

जनमत सर्वेक्षण के खतरे

> यदि कोई राजनीतिक जनमत सर्वेक्षणों पर भरोसा सिर्फ जनता का रुख जानने के लिए करता है तब तो जनमत संग्रह फायदेमंद हैं, किंतु यदि वह पूरी तरह से जनमत संग्रह के निष्कर्षों पर विश्वास कर लेता है, तो उसका नुकसान उठाना लाजिमी है।
>
> **—रिचर्ड निक्सन, पूर्व राष्ट्रपति, अमरीका**

आजकल चुनावों को करीब मानकर देश में जनमत संग्रहों की बाढ़ आयी हुई है। इनमें से अधिकतर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राजीव गांधी को अपनी छवि सुधारने तथा संसदीय चुनाव जीतने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। यही नहीं, हाल में देश की नामीगिरामी समाचार पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में छपे जनमत संग्रह तो इस बात का भी संकेत करते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वे जनता में अपनी ईमानदारी तथा राजीव गांधी के भ्रष्ट चरित्र की बात मनवा सकने में सफल नहीं हुए। किंतु सवाल यह है कि क्या जनमत सर्वेक्षणों पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है?

विदेशी अनुभव: इस संबंध में विंसटन चर्चिल का यह बयान दोहराना अनुचित न होगा कि जनमत संग्रहों द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्णयों पर विश्वास करना भ्रम में रहना है। जाहिर है, चर्चिल ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में जनमत संग्रहों का अनुभव हासिल करने के बाद ही उक्त बयान दिया होगा। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद चर्चिल ब्रिटेन में चुनाव हार गये थे, बावजूद इसके कि सर्वेक्षणों के अनुसार जनता में उनकी लोकप्रियता घटी नहीं थी। तब से लेकर आज तक जनमत संग्रह विवाद का विषय बना हुआ है। इसके बावजूद पिछले लगभग ४० वर्षों में पश्चिमी देशों, खासतौर से ब्रिटेन तथा अमरीका में जनमत सर्वेक्षणों का रिवाज घटा नहीं है। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी जनमत सर्वेक्षणों ने अपना अच्छा खासा स्थान बना लिया है। चूंकि पश्चिमी देशों में ऐसे सर्वेक्षणों पर विवाद जारी है, इसलिए भारत में भी इनकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जाना अनुचित नहीं। जनमत सर्वेक्षणों को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े किये जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं:

- क्या जनमत संग्रहों पर सही राजनीतिक निष्कर्ष देने के लिए विश्वास किया जा सकता है?
- जनमत संग्रह जनता के लिए हितकर हैं या नहीं?
- क्या भारतीय जनता इतनी समझदार है कि प्रश्नदाताओं के सवाल को समझ कर सही उत्तर दे तथा क्या देश की जनता इन सर्वेक्षणों का महत्व समझती है?
- क्या देश में विश्लेषण करने के लिए उचित वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं जिनसे उचित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके?

इस संबंध में मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप (मार्ग) के अध्यक्ष केएमएस टूटू अहलूवालिया का उल्लेख जरूरी है जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत की जनता किसी विषय पर अपना नजरिया प्रचारित करने या करवाने में विश्वास नहीं रखती। अहलूवालिया का कहना है कि आमतौर से यह धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर चूंकि देश के ७५ प्रतिशत मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं इसलिए सर्वेक्षणों के माध्यम से शत-प्रतिशत सही अनुमान लगा पाना आसान बात नहीं।

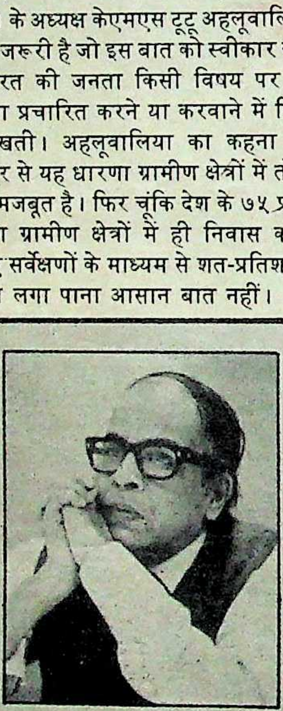

डा० जयदुबाशी का सिद्धांत उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि एजेंसियां प्रश्न तैयार करते समय तथा उत्तरदाता जवाब देते समय स्थानीय समाचार पत्रों के नजरिये से प्रभावित होते हैं तथा मतदाताओं का वास्तविक नजरिया, तो चुनाव के समय ही सामने आता है। मिसाल के तौर पर बड़े शहरों के समाचार पत्रों का जायजा लिया जा सकता है।

स्थिति तो यह है कि भारतीय मतदाताओं को फुसलाने तथा उनमें यह विश्वास पैदा करने के लिए कि उनका नजरिया आम नहीं किया जायेगा, हाल में मार्ग के प्रश्नदाताओं ने 'इंडिया टुडे' के लिए एक छोटे से जनमत संग्रह के दौरान 'बैलट बाक्सों' का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी मार्ग को मनमाफिक परिणाम नहीं मिले। ऐसी स्थिति में जहां उत्तरदाता प्रश्नों का उचित उत्तर देने से कतराता हो, वहां जनमत संग्रहों के आधार पर किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचना कैसे संभव हो सकता है?

देशी नजरिया: इसी तरह जनमत सर्वेक्षणों को लेकर 'इलस्ट्रेटेड वीकली' के पूर्व संपादक तथा वरिष्ठ राजनीतिक प्रेक्षक एमवी कामथ का नजरिया भी ढुलमुल नजर आता है। इस संबंध में पूछे जाने पर वे कहते हैं, "मैं ऐसे जनमत संग्रहों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता।" कामथ का मानना है कि अधिकांश भारतीय अपने अहसास अपने साथियों पर नहीं प्रकट होने देते, तो यह कैसे मान लिया जाये कि वे अपना नजरिया एक ऐसे व्यक्ति के सामने खोल देंगे जिससे उनकी कभी भी जान-पहचान न हो? कामथ कहते हैं, "मैं तो 'वीक' में छपे जनमत संग्रह से कतई सहमत नहीं हूं।" यही नहीं, जब उनसे 'माया' ने 'इलस्ट्रेटेड वीकली' तथा 'इंडिया टुडे' में हाल में छपे जनमत सर्वेक्षणों के बारे में पूछा, तो भी उनका यही कहना था कि 'वीकली' तथा 'इंडिया टुडे' में प्रकाशित जनमत सर्वेक्षण भी किसी रूप में जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस संबंध में उन्होंने कारण यह बताया कि प्रश्नदाता मतदाताओं से जो प्रश्न करते हैं वे क्षेत्र, वर्ग तथा माहौल के हिसाब से बदलते नहीं, जबकि भारत में थोड़ी-थोड़ी-सी दूरी पर विचारों में भिन्नता पायी जाती है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, परंपराओं, आदतों, साक्षरता आदि को नजरअंदाज करते हुए हर जगह एक ही तरह के प्रश्न पूछकर मतदाताओं की मानसिकता का अध्ययन करना कैसे उचित माना जा सकता है?

लगता है, जनमत सर्वेक्षणों की उपर्युक्त खामियों को मद्देनजर रखते हुए ही, कांग्रेस-इ ने नामीगिरामी रीडिफ्यूजन एजेंसी तथा अन्य छवि सुधारक एजेंसियों को विभिन्न क्षेत्रों में हर तीन महीने में सर्वेक्षण करने के लिए लगाया है। चूंकि तीनों एजेंसियां अलग-अलग समय तथा अलग-अलग क्षेत्रों में जनमत्त सर्वेक्षण करेंगी तथा प्रत्येक पंद्रह दिनों में कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेताओं को उनकी स्थिति से अवगत करायेंगी, इसलिए पार्टी को यह विश्वास है कि वह जनमत सर्वेक्षणों के गलत निष्कर्षों से प्रभावित नहीं होगी। यानी ऐसी स्थिति में कांग्रेस-इ के नेताओं का हाथ भारतीय

जनता की नब्ज पर होगा।

सर्वेक्षणों की बाढ़ : यही नहीं, अगले चुनाव की सभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए देश की समाचार पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में भी जनमत संग्रहों की बाढ़ आना स्वाभाविक है। भले ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये जनमत सर्वेक्षणों में भिन्नता पायी जाती है, फिर भी इन सर्वेक्षणों को देश की जनता पढ़ने के लिए उत्सुक रहती है। जहां राजनीतिकों को ऐसे सर्वेक्षणों की प्रतीक्षा रहती है, वहीं मतदाता भी इन सर्वेक्षणों को पढ़कर एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुमान से अवगत होना चाहते हैं। राजनीतिकों तथा मतदाताओं की इसी रुचि के फलस्वरूप देश में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां प्रकाशकों से बड़ी मात्रा में धन उगाह रही हैं। देश में कार्यरत कुछ एजेंसियां जैसे 'मार्ग', 'आईएमआरबी' (इंडियन मार्केट एंड रिसर्च ब्यूरो), ओआरजी (आपरेशन रिसर्च ग्रुप), एमआरएएस-बर्क, इस व्यापार से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। सूत्रों के अनुसार 'मार्ग' द्वारा इस वर्ष दो करोड़ रुपए का व्यापार किये जाने की संभावना है तथा आईएमआरबी का व्यापार ४.५ करोड़ तक जाने की आशा है। संभव है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी आम राजनीतिक अपना हाथ दिखाने तथा भविष्य जानने की पुरानी परंपरा को कायम रखे, किंतु महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस-इ तथा उसके नेता, एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गये सर्वेक्षणों का बारीकी से जायजा लिए बिना उनके निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस तरह के अविश्वास की वजह सिर्फ यह है कि पिछले कुछ मौकों पर नामीगिरामी एजेंसियों के सर्वेक्षण भी चुनाव के समय थोथे साबित हुए हैं। जनमत सर्वेक्षण की इसी कमजोरी ने जनमत संग्रहों को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है।

यह सच है कि देश में सर्वेक्षणों का चलन बढ़ा है। किंतु इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उतनी ही तेजी से सर्वेक्षणों के प्रति अविश्वास भाव भी पनप रहा है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद के संसदीय उपचुनाव के पहले आईएमआरबी ने सुनील शास्त्री की जीत का फैसला सुनाया था, जबकि जीत वीपी सिंह की हुई। इसी तरह हरियाणा में भी सर्वेक्षणों के प्रतिकूल निष्कर्ष सामने आये। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि प्रश्नदाताओं ने या तो ग्रामीण मतदाताओं की मानसिकता को समझने में गलती की थी या जो प्रश्न उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं के सामने रखे, वे गलत थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का यह भी नजरिया है कि ज्यादातर प्रश्नदाता समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में छपे नजरिये को ध्यान में रखकर ही सवाल तैयार करते हैं तथा उन्हीं से प्रभावित होकर सर्वेक्षण का निष्कर्ष भी निकालते हैं। इसी तरह एक वर्ग तो यह भी मानता है कि आमतौर से एजेंसियां भी अपने प्रश्न मौजूदा राजनीतिक हवा तथा महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित अग्रलेखों को मद्देनजर रखते हुए तैयार करती हैं। यहीं पर गलत विश्लेषण की संभावना जन्म लेती है, क्योंकि आजकल विभिन्न राजनीतिक प्रेक्षकों तथा संपादकों के नजरियों में भी आकाश-पाताल का अंतर दिखायी पड़ता है। जहां एक तबका पूर्णरूप से सत्तारूढ़ दल का साथ दे रहा नजर आता है, वहीं संपादकों तथा राजनीतिक प्रेक्षकों का एक गिरोह ऐसा भी है, जो विपक्ष के प्रति सहानुभूति रखता है। इस संबंध में मशहूर राजनीतिक प्रेक्षक डा० जयदुबाशी का सिद्धांत उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि एजेंसियां प्रश्न तैयार करते समय तथा उत्तरदाता जवाब देते समय स्थानीय समाचार पत्रों के नजरिये से प्रभावित होते हैं तथा मतदाताओं का वास्तविक नजरिया, तो चुनाव के समय ही सामने आता है। मिसाल के तौर पर बड़े शहरों के समाचार पत्रों का जायजा लिया जा सकता है।

कामथ बोले, "जब जापान के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए कुरसी छोड़नी पड़ी कि उसने एक गीशा की कीमत अदा नहीं की, तो यह कैसे माना जा सकता है कि जो सरकार ६४ करोड़ की दलाली के आरोप से घबरा-कतरा रही हो उसका नेता ईमानदार होगा?"

अखबारी नजरिया : कलकत्ता से प्रकाशित 'टेलीग्राफ', बंबई, दिल्ली तथा बंगलौर का 'टाइम्स आफ इंडिया' तथा नयी दिल्ली व पटना से प्रकाशित 'हिंदुस्तान टाइम्स' सब ही राजीव गांधी के पक्ष में लिख रहे हैं। इसी तरह मद्रास और दिल्ली से प्रकाशित होनेवाले 'हिंदू' में बोफोर्स संबंधी कुछ दस्तावेज अवश्य छपे हैं, किंतु पारंपरिक ढंग से वह भी सरकार का ही पक्ष लेता है। निस्संदेह उपर्युक्त समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या कम नहीं है कि यह मान लिया जाये कि उनके राजीव के पक्ष में लिखने से जनता पर कोई असर नहीं होता। सचाई तो यह है कि उपर्युक्त समाचार पत्र ही देश की अधिकतर पढ़ी-लिखी जनता द्वारा पसंद किये जाते हैं। डा० दुबाशी का कहना है कि यही वजह है कि बड़े शहरों में किये जानेवाले जनमत सर्वेक्षणों के निष्कर्ष राजीव गांधी तथा उनकी सरकार के पक्ष में जाते हैं।

डा० दुबाशी के अलावा 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस संबंध में प्रकाशित चंदन मित्र का लेख भी काफी निष्पक्ष है। चंदन मित्र लिखते हैं, "राजनीतिक विश्लेषकों को जनता की 'झुंड की मानसिकता' का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विश्लेषकों से गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह अंदाज लगाना आसान नहीं होता कि किसी विशेष घटना का जनता पर क्या असर हुआ तथा मतदाताओं ने उक्त घटना के कारण अपना फैसला बदला या नहीं।" अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मित्र कई मिसालें पेश करते हैं। वे कहते हैं, "जब राजीव गांधी ने विपक्ष के खिलाफ हमलावर नजरिया अपनाया, तो जहां कुछ लेखकों ने उनके इस कदम को वाजिब बताया, वहीं कुछ ने प्रधानमंत्री के इस कदम की भर्त्सना की। बिलकुल ऐसी ही स्थिति जवाहर रोजगार योजना की घोषणा तथा सीएजी रिपोर्ट आने तथा जनरल के सुंदरजी के विस्फोटक रहस्योद्घाटन के समय बनी। तीनों मौकों पर जहां लेखकों तथा प्रेक्षकों की एक जमात ने राजीव सरकार की भर्त्सना की, वहीं दूसरी जमात ने राजीव गांधी का पक्ष लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऐसे में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित विचार से प्रभावित होनेवाला सामान्य मतदाता असमंजस में पड़ जाता है। क्योंकि दोनों ही जमात के लेखकों तथा प्रेक्षकों का यह दावा उसके समक्ष है कि अमुक घटना से जनमत प्रभावित नहीं हुआ।" इसीलिए चंदन मित्र का मानना है कि जनता की 'झुंड-मानसिकता' जनमत सर्वेक्षणों को विश्वसनीय नहीं बनने देती, क्योंकि आमतौर पर जनमत संग्रह बड़े अथवा छोटे शहरों में ही होते हैं, जहां उत्तरदाता अपने पसंदीदा समाचार पत्र अथवा लेखक के विचार से प्रभावित होकर ही उत्तर देता है। सिर्फ चुनाव के समय ही मतदाता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा प्रकट करता है जिसका पूर्व की इच्छाओं से तालमेल नहीं होता।

अविश्वास भाव : यही कारण है कि चुनावों में सर्वेक्षणों के विपरीत परिणाम सामने आते हैं। सर्वेक्षणों के गलत होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि शहरी तथा ग्रामीण मतदाताओं के सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। चूंकि एजेंसियां नपे-तुले बजट में सिर्फ बड़े शहरों में ही जनमत सर्वेक्षण करती हैं, इसलिए चुनाव के

समय ग्रामीण मतदाताओं का नजरिया सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गलत साबित कर देता है। शायद इसीलिए 'वीक' के गोपालाकृष्णन कहते हैं, "जनमत सर्वेक्षणों के निष्कर्ष तभी विश्वसनीय हो सकते हैं जब सर्वेक्षण करनेवाली एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपने सर्वेक्षण में शामिल करें।" दूसरी ओर एजेंसियों का अनुभव यह है कि गांव का मतदाता किसी भी हाल में प्रश्न का सीधा उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होता। इस संबंध में 'संडे आब्जर्वर' के रजत शर्मा कहते हैं, "जो हरियाणा विधानसभा चुनावों के समय हरियाणा में मौजूद था, वही यह जान सकता है कि हरियाणा में सर्वेक्षण के विपरीत परिणाम सामने क्यों आये? वहां तो स्थिति यह थी कि यदि किसी हरियाणवी से यह पूछा जाता कि वह किसको वोट देगा, तो हरियाणवी पलटकर प्रश्नदाता से ही प्रश्न कर बैठता कि पहले वह बताये कि वह किसके पक्ष में है? जाहिर है, ऐसी स्थिति में सही निष्कर्ष तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है? इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक तरीका कारगर नहीं हो सकता।"

भारत में राजनीतिक भविष्यवाणियों के गलत होने का एक कारण यह भी है कि इस देश में मुद्दों के प्रति जनता में बड़े पैमाने पर विरोधाभास पाया जाता है, जबकि विदेशों में एक ही मुद्दा सरकार के लिए हितकर या नुकसानदेह साबित हो जाता है। मिसाल के तौर पर भ्रूण-हत्या किसी खास अमरीकी तबके का मुद्दा नहीं है, अलबत्ता अमरीका का हर नागरिक इस मुद्दे को अपना मसला मानता है। ऐसे में इस मसले पर सरकार का दृष्टिकोण जनता में उसकी विश्वसनीयता तय करता है। किंतु भारत में स्थिति बिलकुल उलटी है। यहां तो हाल यह है कि जहां बिहार का एक किसान सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वहीं महाराष्ट्र के किसान को इस तरह की कोई शिकायत नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कामथ कहते हैं, "विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता के अनुपात में भिन्नता, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विरोधाभास, गरीब तथा अमीर का अंतर, जातीय आधार पर उपजी मानसिकता आदि भारत में जनमत सर्वेक्षण के मार्ग में महत्वपूर्ण अड़चनें हैं, जिनका न तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन संभव है और न ही उनको नजरअंदाज करके उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।" 'माया' ने जब कामथ से इस संबंध में यह कहा कि हाल के सर्वेक्षणों में ६० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ईमानदारी पर मुहर लगायी है, तो कामथ बोले, "मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। यदि सर्वेक्षण सही भी है, तो भी मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि भारतीय जनता इस हद तक नासमझ हो सकती है। जब जापान के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए कुरसी छोड़नी पड़ी कि उसने एक शीशा की कीमत अदा नहीं की, तो यह कैसे माना जा सकता है कि जो सरकार ६४ करोड़ की दलाली के आरोप से घबरा-कतरा रही हो उसका नेता ईमानदार होगा?" कामथ का मानना है कि इस तरह के सर्वेक्षण किसी रूप में भी भारतीय जनता के विचार की अभिव्यक्ति नहीं माने जा सकते।

इस संबंध में रजत शर्मा मोरारजी देसाई के साथ पेश आयी घटना की मिसाल देते हैं। शर्मा उस घटना को याद दिलाते हैं जब एक नामीगिरामी पत्रकार सिमूर हर्ष ने मोरारजी देसाई पर सीआईए का दलाल होने का आरोप लगाया था। हर्ष के इस आरोप से देसाई तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस संबंध में न तो उन्होंने कोई संवाददाता सम्मेलन बुलाया न ही किसी को इस आदेश के साथ विदेश भेजा कि वह जाकर आरोप के प्रतिकूल सबूत लाये। और-तो-और, जनता ने भी देसाई पर लगे आरोप को स्वीकार नहीं किया। नतीजतन जनमत का खयाल करते हुए देसाई की जानी-मानी दुश्मन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में यह बयान दिया था कि देसाई सीआईए के दलाल नहीं हो सकते। शर्मा का कहना है कि इसे कहते हैं जनमत का रुख जिससे मजबूर होकर दुश्मन भी जनता की भाषा बोलने लगते हैं। किंतु यदि उस समय भी जनमत संग्रह कराया जाता, तो उत्तरदाताओं का ज्यादा अनुपात देसाई पर संदेह करता हुआ पाया जाता।

खतरे : किंतु यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर १९८४ के सभी सर्वेक्षण खरे क्यों साबित हुए? इस सवाल के जवाब में सिर्फ यह कहना ही काफी होगा कि '८४ के सर्वेक्षणों के सही होने के पीछे कारण यही था कि सर्वेक्षण चुनाव के ऐन पूर्व कराये गये थे तथा उस समय पूरे देश में एक ही तरह की हवा बह रही थी। देश के हर नागरिक के समक्ष केवल देश की सुरक्षा और अखंडता ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन आज देश की जनता के समक्ष ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर जनता एक हो गयी हो तथा देश में एक-सी हवा बह रही हो।

एचके दुआ की बात उल्लेखनीय है, "मैं जनमत सर्वेक्षणों के पक्ष में नहीं, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में, जहां थोड़ी-थोड़ी-सी दूरी पर भिन्नताएं पायी जाती हों, वहां 'नमूने' खड़े करके देश की जनता के वास्तविक रुझान का सही अंदाज लगाना संभव नहीं।"

ऐसी स्थिति में जब देश में कोई हवा न बह रही हो तथा क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे बदल रहे हों, जनमत संग्रह के माध्यम से किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नजर नहीं आता। किंतु इसका यह मतलब कतई नहीं कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को इस तरह के सर्वेक्षण छापना बंद कर देना चाहिए। इसी देश में एक तबका ऐसा भी है जो यह मानता है कि जनमत सर्वेक्षणों का भारतीय जनता पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का मतदाता जो अपने विचार किसी पर व्यक्त करना उचित नहीं समझता, वह शहरी नजरिये को सुन-पढ़कर भी अपनी राय बनाता है। किंतु यह कहना कि ग्रामीण मतदाता पूर्ण रूप से सर्वेक्षणों को ही आधार बनाकर फैसला करता है, सरासर गलत होगा, क्योंकि यदि सर्वेक्षणों से वह प्रभावित होता, तो अब से पहले कई मौकों पर सर्वेक्षणों के विश्लेषण गलत साबित न होते।

बात घूम-फिरकर फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाती है कि जब तक देश में किसी मुद्दे पर एक-सी हवा न बह रही हो, कुछ शहरों में मतदाता से प्रश्न करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। हां, इतना जरूर है कि ऐसे सर्वेक्षणों से समय-समय पर जनता के सोच का अंदाज जरूर मिलता है। किंतु चुनाव के समय तक जनता उसी ढंग से सोचती रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में 'हिंदुस्तान टाइम्स' के संपादक एचके दुआ की यह बात उल्लेखनीय है, "मैं जनमत सर्वेक्षणों के पक्ष में नहीं, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में, जहां थोड़ी-थोड़ी-सी दूरी पर भिन्नताएं पायी जाती हों, वहां 'नमूने' खड़े करके देश की जनता के वास्तविक रुझान का सही अंदाज लगाना संभव नहीं।" कुछ इसी तरह की बात प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के निदेशक प्रकाश 'रा कहते हैं, "जनमत सर्वेक्षणों के लिए मैं इतना ही कहना काफी समझता हूं कि उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारत में लोगों के सोचने के ढंग तथा जनमत सर्वेक्षणों के विश्लेषण में बड़ा अंतर देखा जा रहा है।" ऐसे में राजीव गांधी तथा उनकी जमात अपने पक्ष में सर्वेक्षणों को देखकर यदि निश्चिंत हो जाती है, तो निक्सन के अनुभव के अनुसार उसे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

—विजय

DIPLOMAT
महफ़िल की जान
यह नई शान!
McDowell's
DIPLOMAT
DISPOSABLE
ICE CUBE BAGS
The new
smooth choice!
McDOWELL & CO. LTD.
McDowell's
DIPLOMAT

युवा मानसिकता और चुनावी पसंद

भारतीय राजनीति के इतिहास के प्रवाह को मोड़ देने में युवा शक्ति ने अनेक बार निर्णायक भूमिका निभायी है। १९४२ के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के समय जब बड़े नेता जेल में बंद कर दिये गये थे और कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गयी थी, तो ये नौजवान ही थे, जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' के नारे गुंजाने और साकार करने में भी युवकों की ही अनुकरणीय भूमिका रही थी। विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद युवकों के आंदोलन की धारा ने दूसरा मोड़ ले लिया। चाहे वह भाषा-आंदोलन रहा हो या नक्सलवादी आंदोलन, नवयुवक ही हमेशा हरावल दस्ते में रहे हैं। युवकों की अपराजेय शक्ति का सर्वाधिक अहसास जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण-क्रांति के आंदोलन के समय हुआ, जब युवकों ने पूरे देश में परिवर्तन की आंधी ला दी थी। इसी का परिणाम था—आजादी के इतिहास में पहली दफा १९७७ में केंद्र से कांग्रेस की सत्ता का सफाया। मतदान की उम्र २१ वर्ष से घटाकर १८ वर्ष कर देने के बाद मतदाताओं में युवाओं की निर्णायक भूमिका हो गयी है। इन युवा मतदाताओं के राजनीतिक झुकाव को परखने का एक मार्ग है 'जनमत सर्वेक्षण' और दूसरा है, उन स्थितियों-समस्याओं का विश्लेषण जो इनको किसी दल या नेता का समर्थन देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इन युवा मतदाताओं की मानसिकता क्या है और ये किस पार्टी की ओर झुक सकते हैं? प्रस्तुत है, 'माया' का विश्लेषण :

ऐसा नहीं है कि युवक अब से पहले मतदान नहीं करते थे। जब मतदान की उम्र २१ वर्ष थी, तब १५-१६ साल का युवक मतदाता-सूची में २१ साल का दर्ज होकर धड़ल्ले से मतदान करता रहा है। अब १८ साल के युवक को मताधिकार मिल गया है, इसलिए अब मतदाताओं की पांतों में ऐसे चेहरों की भरमार होगी, जिनकी मसें भी अभी नहीं भीगी हैं। इसलिए इस बार जवानी का तूफानी उत्साह चुनाव को बेइंतहा गरमायेगा। यह उत्साह किस पक्ष की थाती बनेगा, इसकी पूरी थाह जनमत सर्वेक्षण से मिलना संभव नहीं है। युवा वर्ग की समस्याओं के मार्ग से गुजर कर ही उनके राजनीतिक रुझान को रेखांकित किया जा सकता है।

देश के युवा मतदाताओं में सौ में से सिर्फ चार ही ऐसे हैं जो कालेज या विश्वविद्यालय का मुंह देख पाते हैं, लेकिन इन चार में भी उन युवकों की संख्या आधी से अधिक नहीं होती जो विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने में सफल रहते हैं। उनमें से भी कुछ ही युवक प्रशासनिक सेवाओं या किसी बैंक के प्रोबेशनरी अधिकारी या निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक अधिकारी के पदों के लिए प्रतियोगी बन पाते हैं। जो युवक स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से कुछ विद्यालयों में शिक्षक बनते हैं। बहुत कम युवक ऐसे होते हैं, जिन्हें महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनने का अवसर प्राप्त होता है। शेष सभी ९६ प्रतिशत युवक खेतों, फैक्ट्रियों और कार्यालयों में छोटी-मोटी नौकरी करते हैं या छोटा-मोटा धंधा।

युवा वर्ग की श्रेणी : मतदान की आयु कम करने से भारत के मतदाताओं में इस बार छह

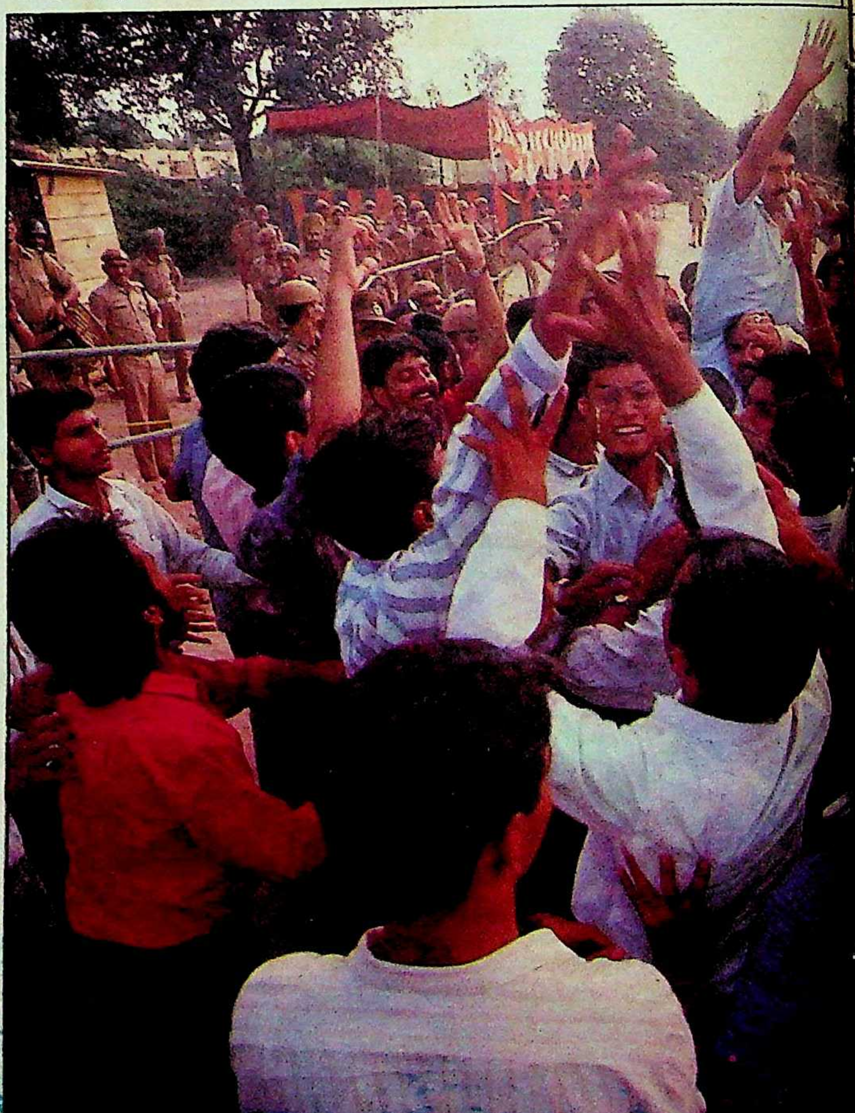

छाया : धाना इंडिया

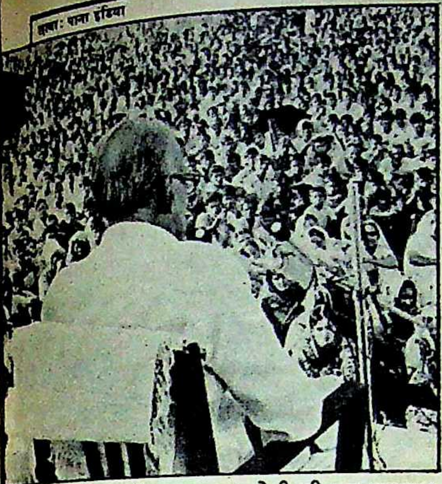

जेपी आंदोलन की जान-युवक : जेपी की एक जनसभा

छाया : एस पाल

करोड़ नये मतदाताओं का इजाफा हुआ है। लेकिन यदि देश के समस्त युवा वर्ग की संख्या का निर्धारण करना है, तो पहले यह तय करना होगा कि युवा वर्ग की श्रेणी में किस वय तक लोगों को शामिल किया जाये। कुछ लोगों की मान्यता है कि ३५ वर्ष तक की वयवालों को युवा मानना चाहिए, लेकिन निर्विवाद रूप से सभी यह मानते हैं कि तीस वर्ष को युवावस्था की सीमा रेखा माना जा सकता है। इस प्रकार १८ वर्ष से ३० वर्ष की वय के युवकों की संख्या १९८९ के उत्तरार्ध में १७ करोड़ हो जाती है, जिनमें छह करोड़ वे युवक शामिल हैं, जिनकी आयु १८ से २० वर्ष के बीच है। यह अलग बात है कि नौवीं लोकसभा के लिए होनेवाले मतदान में मतदान करनेवाले नये युवा मतदाताओं की संख्या छह करोड़ न हो, क्योंकि सभी नये मतदाता मतदाता सूंची में अपने नाम दर्ज नहीं करा पाये हैं, तभी तो चुनाव आयोग ने नये मतदाताओं की संख्या साढ़े चार करोड़ बतायी है। इस तरह ऐसे युवकों की संख्या करीब डेढ़ करोड़ है जो १८ से २० वर्ष तक के आयु वर्ग में होने के बावजूद मतदाता सूची में नाम न होने के कारण मतदान नहीं कर पायेंगे।

अग्नि परीक्षा : एनएसयूआई की रैली में राजीव

युवा वर्ग में विभिन्नताएं : देश के इस युवा वर्ग में सिर्फ एक बात समान है कि वे सभी समान आयु वर्ग के हैं, अन्यथा उनमें कोई समानता नहीं है। बिहार या राजस्थान के दूरदराज के गांवों के कभी स्कूल का मुंह न देखनेवाले और बचपन से ही मेहनत-मजदूरी में लगे युवक और शहर के जींस पहने डिस्को डांस करनेवाले युवक के बीच कोई समानता हो भी कैसे सकती है। देश के युवा वर्ग को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है—मसलन, शहरी-ग्रामीण, पुरुष-स्त्री, हिंदू-सिख-मुस्लिम-ईसाई, पिछड़े और अनुसूचित जाति व जनजाति, शिक्षित-अशिक्षित आदि। इन वर्गों के बीच भी आमदनी, नौकरी एवं भाषागत अनेक विभेद हैं।

देश के शहरी क्षेत्रों—खासकर बड़े शहरों और महानगरों—में बड़ों और युवकों में साफ अंतर है। समाज में जब भी कोई परिवर्तन होता है, उसका प्रवेश पहले शहरों में होता है। शहर के सफेदपोश नौकरीपेशा और पेशे विशेष में लगे लोगों के बेटी-बेटे आमतौर पर शहरी मध्य वर्ग में आते हैं। इनमें ज्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और बीए, एमए करने के बाद स्थायी रोजगार के आकांक्षी होते हैं। देश के विश्वविद्यालयों और कालेजों के लगभग ४० लाख विद्यार्थियों में २५ लाख से अधिक शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और इनमें ७ लाख से अधिक महानगरों में रहने वाले हैं। जो युवक उच्च शिक्षा संस्थानों में होते हैं, उनकी उम्र १७ और २२ वर्ष के बीच होती है। शहरी क्षेत्रों के इस आयु-समूह के लड़कों और लड़कियों की संख्या १.७५ करोड़ है। इसका मतलब है कि १०० युवक-युवतियों में १३ ही ऐसे होते हैं जो कालेज में पहुंचते हैं, शेष ८७ नौकरी के इंतजार में घर बैठे रहते हैं। अधिकांश लड़कियां बिना किसी स्वतंत्र आर्थिक हैसियत के शादी कर लेती हैं। शेष शादी तय होने के इंतजार में रहती हैं।

जो बीए और एमए करते हैं, उनमें से कितने ऐसे होते हैं, जिनको ठीक-ठीक जिंदगी गुजारने लायक रोजगार मिल पाता है? प्रतिवर्ष केवल ५ से ६ हजार युवक केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक या पुलिस सेवा में पहुंच पाते हैं। लगभग इतने ही बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारी बन पाते हैं और लगभग ४ हजार तक व्यावसायिक अधिकारी हो पाते हैं। कुछ स्कूल-कालेजों के अध्यापक, वकील, डाक्टर, इंजीनियर और अन्य सफेदपोश तकनीकी कर्मचारी बन जाते हैं। शेष क्लर्क, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक आदि पेशों में नसीब तलाशते हैं। देखा जाये, तो २,५०० रुपए और इससे ज्यादा प्रतिमाह वेतन पाने वालों की संख्या ३५,००० से ज्यादा नहीं है। इनमें उपर्युक्त २० हजार उच्च नौकरीपेशा लोग भी शामिल हैं।

लगभग १३ करोड़ युवक-युवतियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें से १८ और २० वर्ष के बीच की उम्र के थोड़े से युवक-युवती हायर सेकंडरी के विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा देर से शुरू होती है। ग्यारहवीं कक्षा तक भी कुछ भाग्यशाली ही पहुंच पाते हैं। १७ वर्ष के ग्रामीण युवकों का पांचवां हिस्सा ही यहां तक पहुंचता है। पूरे देश में यह अनुपात एक-चौथाई है। अधिकांश ग्रामीण युवकों के पास या तो कोई काम नहीं है या फिर वे खेतिहर मजदूर हैं या फिर अपने खेतों में काम करते हैं। इनमें दसवें हिस्से में वे परिवार आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं और जिनके लिए जवाहर रोजगार योजना लागू की गयी है। कुल मिलाकर ग्रामीण समाज के साढ़े छह करोड़ युवा सदस्यों को पूरा आहार नहीं मिल पाता है। इनमें से ज्यादातर अशिक्षित हैं। कुछ लोग चौथे-पांचवें या आठवें दर्जे तक पढ़े हैं।

आय और रोजगार की बात को अलग करके देखा जाये, तो देश के ४ करोड़ युवक अनुसूचित जाति से संबद्ध हैं और डेढ़ करोड़ मुस्लिम हैं। यहं भी उल्लेखनीय है कि देश के युवा

एक समान नहीं हैं। टीवी, वीडियो कैसेट, स्कूटर, फैशनेबल कपड़े या कंप्यूटर तक सबकी पहुंच नहीं है। इसी तरह उनकी भाषा, परंपराएं, जातियां, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव भिन्न हैं।

अपेक्षाएं: उस नौजवान की पहली आवश्यकता क्या होती है जो मैट्रिक या स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद रोजगार दफ्तर से साक्षात्कार के बुलावे का इंतजार कर रहा है? जाहिर है, एक अदद पक्की नौकरी, जिससे उसको न्यूनतम अपेक्षित आमदनी हो सके। उसकी पहली पसंद होती है—कोई भी नौकरी मिल जाये। दूसरी पसंद होती है, वह नौकरी जो उसकी रुचि की है।

दूसरी पसंद का पूरा होना लगभग नामुमकिन है। पहली पसंद के पूरा होने के इंतजार की घड़ियां भी दीर्घ से दीर्घतर होती जाती हैं। ऐसी हालत में उसे समय काटने के लिए कोई शगल चाहिए। कुछ नहीं है, तो फिल्म ही सही—बशर्ते वह बेरोजगार शहर या कस्बे में रहता हो। लेकिन जेब खर्च कहां से आयेगा? काफी माता-पिता तो ऐसे हैं जो अपने बेरोजगार बेटे को यह जेब खर्च दे ही नहीं सकते, जो दे सकते हैं वे देना नहीं चाहते।

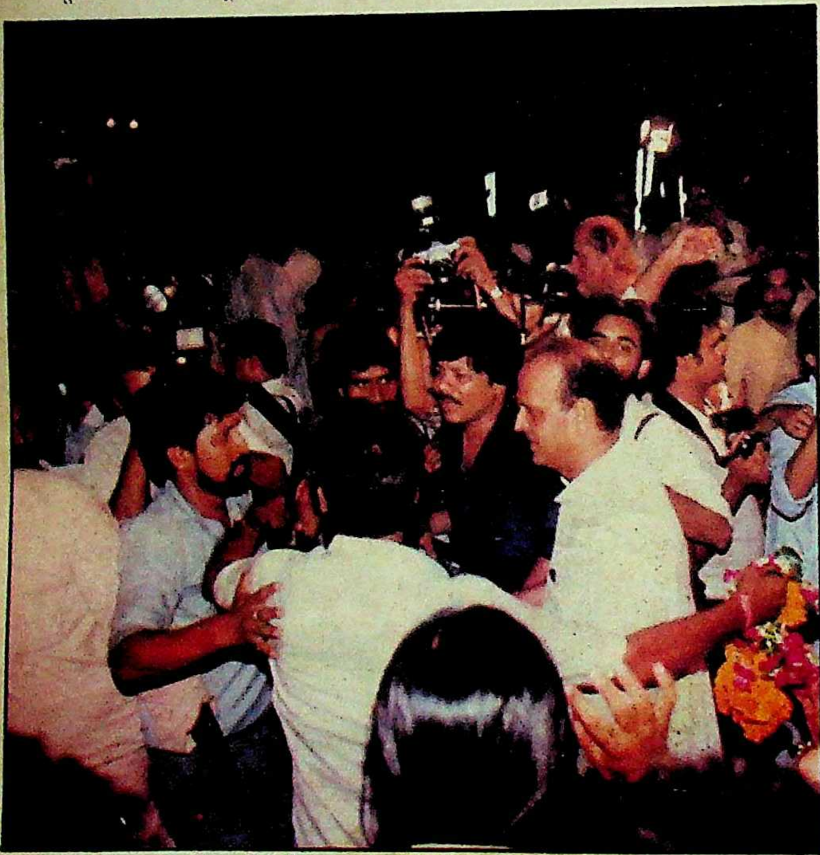

इलाहाबाद उप चुनाव में युवकों ने जिताया: युवकों से घिरे वीपी सिंह

छाया: मनमोहन शर्मा

इस अपमान से खीजते नौजवान को जब साक्षात्कार का बुलावा मिलता है, तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब भावी नियोजक उसे रद्द कर देता है, तो अपमान का कांटा भाले की तरह चुभने लगता है। ऐसी ही हताशा की अंधेरी सुरंग में वह नौजवान पहुंचता है, जो यह देखता है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए प्रत्याशियों की सूची में उसका नाम नहीं है।

यदि वह मैट्रिक है, तो सोचता है, अगर उसे कालेज में दाखिला मिल जाता, तो वह नौकरी के लिए कुछ साल और इंतजार कर सकता था। उसको उम्मीद होती है कि शायद बीए हो जाने के बाद नौकरी के बाजार में उसकी वकत और बढ़ जाये। लेकिन आज कालेजों और विश्वविद्यालयों में करीब ४० लाख ही विद्यार्थी खप पा रहे हैं, जबकि मैट्रिक पास करनेवालों की संख्या एक करोड़ छह लाख से ज्यादा है।

इसलिए ज्यादातर रोजगार की तलाश करते हैं। लेकिन वह मिलता कहां है। रोजगार दफ्तरों के आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारों की संख्या १९८८ में एक करोड़ ६७ लाख थी। इनमें लगभग ९७ लाख मैट्रिक थे। बचे हुए ७० लाख में बीए, एमए थे। १९८२ में मैट्रिक बेरोजगारों की संख्या ५६ लाख थी और बीए बेरोजगारों की ३० लाख।

इन लोगों का और १९९० में मैट्रिक या बीए करनेवालों का भविष्य शुद्ध अंधकारमय है। १९८५ में शिक्षित लोगों की संख्या ४ करोड़ ८० लाख (अब लगभग ५ करोड़) थी। इनमें से लगभग आधे लोग बेरोजगार हैं।

किसको वोट देंगे: इनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो नये मतदाता हैं। इन सभी को आगामी चुनाव में अपनी पसंद को जाहिर करना है। ये मतदाता राजीव गांधी को वोट देंगे या किसी अन्य नेता को? देखा जाये, तो नौजवान हर किसी से क्रुद्ध हैं। अधिकांश को कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जो उन्हें प्रेरित कर सके, उनमें आदर्श का संचार कर सके। लेकिन उसे इसका सीधा अनुभव नहीं है कि विपक्ष कैसे शासन चलाता है। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि केंद्र में दूसरी सरकार आती है, तो उन्हें नौकरीं मिल ही जायेगी। दूसरी ओर उन्होंने राजीव सरकार को भी देख लिया है जो उनमें रोजगार के लिए पर्याप्त आशा का संचार नहीं कर पायी है। शुद्ध रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाये, तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि वे राजीव गांधी को वोट देंगे।

जिन घरों को खेती से अच्छी आय है, उनके युवा सदस्य आमतौर पर पिता के व्यवसाय को अपना कर खुश नहीं होते, चाहे इस पेशे के कारण ट्रैक्टर, अनेक दुधारू पशु और रंगीन टीवी आदि वस्तुएं परिवार ने क्यों न जुटा ली हों। ये नौजवान अपनी तुलना संपन्न बिजनिस एक्जीक्यूटिव, युवा प्रशासक या राजनेता से करते हैं, जिनकी शक्ति और सत्ता का चारों ओर बोलबाला होता है।

यह सत्ता और स्टेटस का आकर्षण ही है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जाट युवकों को विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रसंघों के चुनावों में जी-जान लगा देने को बाध्य करता है। बंदूकें, मोटर साइकिल और अल्कोहल जैसी चीजें, बनारस, इलाहाबाद, जबलपुर, सागर, भोपाल, पटना आदि विश्वविद्यालयों के छात्रों की प्रतिष्ठा-प्रतीक बन गयी हैं। हो सकता है सत्ता के करीब होने के कारण सत्तादल की ओर ये युवक झुकें, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम होगी।

दूसरी ओर, ग्रामीण युवतियां पारंपरिक मूल्यों और हर हाल में आज्ञाकारी बने रहने पर जोर देने वाली आचार संहिता के आवे में लगातार तप रही हैं। विचार स्वातंत्र्य का या तो उन्हें बोध ही नहीं या होता है, तो फिर वह घोर अपराध कहलाता है। उनके लिए विचार सामाजिक दृष्टि से एक अवांछनीय चीज है। हां घरेलू कामों, पति-पिता या सास-ससुर की सेवा के बारे में सोचने की उन्हें छूट है। बहुधा १५ या इससे कम उम्र में विवाह उनकी नियति है और मातृत्व, कुपोषण के कारण बीमार संतान की देखभाल उनकी जीवनचर्या है।

महिला शिक्षा, स्त्री मुक्ति आंदोलनों और काफी संख्या में महत्वपूर्ण सफेदपोश नौकरियों में लगने के बावजूद देश के लगभग साढ़े पांच लाख गांवों की युवतियां अपनी माताओं की तरह ही

सोचने के लिए अभिशप्त हैं। वे वोट देने का निर्णय भी अपनी माताओं की तरह ही करती हैं। जाहिर है, माताओं का निर्णय उनके पतियों का निर्णय होता है।

देश के १५ करोड़ युवा मतदाताओं में इन युवतियों की संख्या ६ करोड़ से ज्यादा है। लगभग सवा दो करोड़ ऐसी युवतियां हैं जो १८ से २० वर्ष के आयु समूह में हैं। लेकिन चाहे २० वर्ष की हों या २५ की, मोहर लगाने के लिए चुनाव चिह्न के चयन में उनका मापदंड लगभग एक सा है। इसलिए स्थानीय निकायों में ३० प्रतिशत आरक्षण या महिलाओं को लुभानेवाली ऐसी अन्य योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को वोट देने के मामले में अपने पतियों से भिन्न निर्णय लेने के लिए शायद ही बाध्य कर सकें।

जिंदगी की हकीकत : बड़ी महत्वाकांक्षाओं से रहित ग्रामीण युवकों पर यह बात लागू नहीं होती कि युवा दिमाग हर चीज को भिन्न तरह से लेता है। बेशक दिमाग जवान है, लेकिन असली जिंदगी के अनुभव पिता के अनुभवों से ज्यादा भिन्न नहीं होते। हरिजन का बेटा हरिजन ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे अपंने खेतिहर मजदूर पिता के व्यवसाय से बंधा पुत्र खेतिहर मजदूर होता है। जहां पहली पीढ़ी पढ़-लिखकर अपने पुश्तैनी धंधे से मुक्ति पा लेती है, वहां अपवाद हो सकते हैं। लेकिन ऐसे अपवाद बहुत कम हैं। नतीजतन हरिजन युवक और खेतिहर युवा मजदूर की असली जिंदगी के अनुभवों का संबंध रोजगार, आय, खाने-पीने के स्तर और शिक्षा तक पहुंच से है। अगर जवाहर रोजगार योजना उसे ज्यादा काम, ज्यादा खाना और ज्यादा उम्मीदें देती है, तो उसके पास राजीव गांधी को वोट देने के ज्यादा कारण हैं। वह राजीव गांधी को इसलिए वोट नहीं देगा, क्योंकि वह हरिजन युवक है या युवा खेतिहर मजदूर है, बल्कि इसलिए देगा, क्योंकि वह हरिजन है या खेतिहर मजदूर है। यहां उम्र भूमिका नहीं निभायेगी, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति की भूमिका होगी।

जहां तक शहरी युवकों का सवाल है, मध्यवित्त परिवारों के युवा सदस्यों का छोटा हिस्सा राजीव-सरकार की ओर झुक सकता है। यह वह वर्ग है, जिसको उत्पादन की उपभोक्तावादी प्रणाली का लाभ मिला है। लेकिन बढ़ी हुई उपभोक्तावादी आकांक्षाओं ने व्यापक असंतोष को भी जन्म दिया है। बेरोजगारी और कीमतों में बढ़ोतरी ने नयी आशाओं की पूर्ति के मार्ग में अडिग दीवारें खड़ी कर रखी हैं।

वास्तविक लाभ जिनको मिला है, वे चार करोड़ शहरी युवाओं में से कुछ ही लाख हैं। बाकी पर पत्र-पत्रिकाओं का असर हो रहा है और आगे भी होगा। यह मीडिया भ्रष्टाचार, राजनीतिक तिकड़म और सत्ता केंद्र में जारी गुटबाजी की कहानियां छाप रहा है। जाहिर है, युवक-युवतियों में आदर्शवाद होता है और वे व्यक्तिगत जीवन और राजनीति में ईमानदारी की कद्र करते हैं।

जनमत सर्वेक्षण चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इन सारी स्थितियों से स्पष्ट है कि मध्यवर्गी नौजवानों में से अधिकांश, खासकर शहरी नौजवानों के सत्तारूढ़ दल की ओर झुकने की संभावना नहीं लगती। ग्रामीण नौजवान एक नौजवान के रूप में वोट नहीं देंगे, बल्कि जिस वर्ग और समूह से उनका संबंध है, उसके सदस्य के रूप में वे वोट देंगे। यदि हरिजन या खेतिहर मजदूरों का वर्ग कांग्रेस-इ को वोट देगा, तो ये युवक भी कांग्रेस-इ को ही वोट देंगे।

लेकिन बहुत संभावना है कि सत्तारूढ़ दल को आगे चलकर यह पता चले कि मतदान की उम्र घटा कर उसने अपने वोटों का प्रतिशत भी घटा लिया है। शहरी मतदाताओं में कांग्रेस विरोधी युवा मतदाता अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में होंगे। जबकि ग्रामीण युवा मतदाता अपने बड़ों की लीक पर चलकर वोट देंगे। लेकिन एक बात तय है कि युवक विद्रोही स्वभाव के होते हैं और यह विद्रोह चुनाव के समय अकसर सत्तासीन लोगों के विरोध का पर्याय होता है।

—कुमारेश चक्रवर्ती

प्रमुख राज्यों और क्षेत्रों में युवा मतदाता

(संख्या दस लाख में)

	१८-२१ वर्ष		२१-३० वर्ष	
प्रांत/क्षेत्र	ग्रामीण मतदाता	शहरी मतदाता	ग्रामीण मतदाता	शहरी मतदाता
हिंदी भाषी क्षेत्र	१९.९५	४.२४	३७.०२	८.६२
दक्षिण प्रांत	१०.२७	३.७२	१९.०६	६.८०
महाराष्ट्र	३.४६	१.८७	६.४२	३.४४
गुजरात	१.९९	०.९०	३.६९	१.६४
उड़ीसा	१.९८	०.२६	३.६७	०.४८
प० बंगाल	३.४१	१.२२	६.३३	२.२६
अन्य प्रांत व केंद्रशासित क्षेत्र	४.८४	२.०४	९.०४	३.२२
योग	४५.९०	१४.२५	८५.२३	२६.४६

युवा मतदाताओं में विद्यार्थियों की संख्या काफी है। इन विद्यार्थियों पर किस दल का प्रभाव है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि किस राज्य के विश्वविद्यालयों के अधिकांश छात्र संघों पर किस दल की छात्र शाखा का कब्जा है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह परिदृश्य कुछ इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश : एबीवीपी तथा एनएसयूआई
राजस्थान : एबीवीपी
उड़ीसा : वामपंथी तथा एबीवीपी
उत्तर प्रदेश : एबीवीपी, एनएसयूआई, वामपंथी
गुजरात : एबीवीपी
उत्तर पश्चिम : एसएफआई
बिहार : कोई यूनियन नहीं है
महाराष्ट्र : शिवसेना तथा एबीवीपी
केरल : केएसयू
आंध्र प्रदेश : वामपंथ
पश्चिम बंगाल : एनएसयूआई
कर्नाटक : ज्यादा छात्र संगठन सक्रिय नहीं हैं

नोट : अखिलभारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) भाजपा, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई) कांग्रेस, स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी तथा केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) कांग्रेस का छात्र संगठन है।

—नवनीता सरकार द्रोण

रामलखन सिंह यादव का क्षोभ

बिहार की कांग्रेसी राजनीति में यादवों के मसीहा कहे जानेवाले रामलखन सिंह यादव ने यह क्यों कह दिया है कि आगामी चुनाव में बिहार में कांग्रेस को यादवों का वोट मिलना मुश्किल है?

उपेक्षा का दर्द: रामलखन सिंह यादव

बिहार के पड़ोसी प्रांत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यादव मतदाताओं की घेरेबंदी करने के लिए न सिर्फ बलराम सिंह यादव को बहुत पहले से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुरसी पर बिठा रखा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव जैसे महारथियों को भी बटोर रखा है। पर बिहार में कांग्रेस ने यादव मतदाताओं को अपनी तरफ खीचने के लिए अभी तक कोई कारगर प्रयास नहीं किया है। उलटे बिहार की कांग्रेसी राजनीति में यादवों के पोप माने जानेवाले रामलखन सिंह यादव अपनी उपेक्षा से तुनककर बयान जारी कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को यादव वोट शायद ही मिले। सितंबर के पहले सप्ताह में रामलखन सिंह यादव यह कहते हुए बेसाख्ता फूट पड़े कि बिहार मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल न कर उनका जो अपमान किया गया है, उससे बिहार के यादवों को गहरा सदमा पहुंचा है। रामलखन सिंह यादव ने जब बयान में यह कह दिया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री बलिराम भगत के विरोध के कारण ही वे मंत्री पद से वंचित रह गये, तो पटना के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गयी कि अब तो यादवों के पोप ने भी डा० जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल, रामलखन सिंह यादव के इस बयान के तुरंत बाद बिहार विधानसभा में जनता दल के नेता लालू यादव ने उनसे अनुरोध किया कि कम-से-कम अब तो वे जनता दल में आ ही जायें। लालू यादव 'माया' से कहते हैं, "रामलखनजी का यह बयान पढ़कर कि वे कांग्रेस से दुखी हैं, मैंने उन्हें जनता दल में आने का आमंत्रण दिया। बिहार के यादव मतदाताओं को लुभाने के लिए हम रामलखनजी को जनता दल में आने का न्यौता दे रहे हों, ऐसी बात नहीं। यादव मतदाता तो पहले से ही जनता दल के साथ हैं। यादव वोटरों पर रामलखनजी का कोई बहुत प्रभाव भी नहीं। दरअसल, कांग्रेस में जो नेता निराश्रित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें जनता दल शरण देने को तैयार है। रामलखन सिंह यादव और डा० जगन्नाथ मिश्र दोनों नेताओं को जनता दल में आ जाने का आमंत्रण हमने दिया है।"

फुलपरास की इंका विधायक हेमलता यादव 'माया' से कहती हैं, "विगत संसदीय व विधानसभाई चुनावों में यादवों के सर्वाधिक वोट कांग्रेस को मिले। पर इस बार बिहार में यादव-वोट उसे कैसे मिलेगा, इस मसले पर कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने यादव मतों के लिए पूरी तैयारी कर ली है, पर बिहार में इस नजरिये से कुछ नहीं सोचा गया है।"

साक्षात्कार: रामलखन सिंह यादव

कांग्रेस को मेरी आवश्यकता नहीं है

रामलखन सिंह यादव बिहार की कांग्रेसी राजनीति में कोई मोम के पहलवान नहीं हैं। यही वजह है कि लगातार २२ वर्षों से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद वे सत्ताधारी दल की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। वनवास के इन सुदीर्घ दग्ध वर्षों में वे कभी उखड़े भी नहीं थे। पर हाल में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में जब वे पहले की भांति फिर हाशिये पर छोड़ दिये गये, तो दो दशकों से संचित उनका गुस्सा स्वाभाविक रूप से जहरीला हो उठा। 'माया' से उनकी बातचीत के अंश:

सत्ता से दूरी: मिश्र से दूर बैठे रामलखन सिंह यादव (एकदम बायें)

माया: आपने बयान दिया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री बलिराम भगत के कड़े विरोध और षड्यंत्र के कारण आप मंत्री नहीं बनाये गये। किस आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं?

यादव: जिन परिस्थितियों में मुझे बार-बार अपमानित होना पडा है, उसी आधार पर इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मैं विवश हुआ हूं। दरअसल, जगन्नाथ मिश्र नहीं चाहते हैं कि सत्येंद्रनारायण सिंह और मेरा समीकरण बने, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर ऐसा सचमुच हो गया, तो कांग्रेस में उनकी पूछ खतम हो जायेगी। कई मौकों पर हास-परिहास के बहाने जगन्नाथ मिश्र ने मुझसे कहा भी कि वे भला मुझे कैसे आगे बढ़ने देने का खतरा मोल ले सकते हैं?

सिर्फ जगन्नाथ मिश्र को ही क्या दोष दूं? मैंने जिन-जिन लोगों के लिए किया, वे ही मेरी जड़ खोदते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलिराम भगत इन्हीं में से एक हैं। बलिराम भगत समस्तीपुर के वासी हैं और पटना सिटी में आकर बस गये। १९५२ में वे पटना क्षेत्र से टिकट के लिए प्रत्याशी थे। पर पटना से सारंगधर सिंह को टिकट मिल गया और बलिराम भगत बिलकुल हताश हो गये। ऐसी ही स्थिति में बलिराम भगत को मैं अपने गृह-क्षेत्र आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ाने ले गया था। बलिराम भगत आरा जाने में घबड़ा रहे थे और अंत तक मुझसे कहते रहे, "आरा से भला मैं कैसे लड़ सकता हूं, मुझे तो वहां कोई पहचानता भी नहीं।" पर मैंने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे चुनाव की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। एड़ी-चोटी एक कर बलिराम भगत को मैंने उस चुनाव में सफलता दिलवायी। वही बलिराम भगत आज मेरे दुश्मन बने हुए हैं। इस बार मंत्रिमंडल-विस्तार के समय दिल्ली में उन्होंने भी मेरा भयंकर विरोध किया। संसद के सेंट्रल हाल में सत्येंद्र बाबू के सामने बलिराम भगत से मेरी झड़प भी हो गयी थी। मैंने आखिर उनसे पूछा कि वे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं?

माया: आपने बयान दिया है कि आपको बिहार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इससे पिछड़ों के वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे?

यादव: मेरे संग लगातार जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उससे सबको बेहद अफसोस है। मैं कोई संन्यासी नहीं हूं। पर पद के पीछे जीवन में कभी नहीं भागा। मैंने इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में दिखाया है कि बिना पद पाये कोई कांग्रेसी कितनी निष्ठा से अपनी पार्टी की सेवा कर सकता है। अगर राजीवजी तथा सत्येंद्र बाबू ने उचित समझा हो कि मुझे दल के हित में अवसर दिया जाना ठीक नहीं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का अहित बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद कांग्रेस को मेरी कोई आवश्यकता नहीं। पर पार्टी में अपनी महत्वहीनता समझते हुए भी मैं पार्टी का दासानुदास रहूंगा ही। जहां तक यादव वोटों का सवाल है, तो मेरे अपमान से यादव जरूर आवेश में हैं। मैं कह नहीं सकता कि उनका यह आवेश किस रूप में फूटेगा?

—विकु झा

बलिराम भगत

बलिराम भगत आज मेरे दुश्मन बने हुए हैं। इस बार मंत्रिमंडल-विस्तार के समय दिल्ली में उन्होंने भी मेरा भयंकर विरोध किया। संसद के सेंट्रल हाल में सत्येंद्र बाबू के सामने बलिराम भगत से मेरी झड़प भी हो गयी थी। मैंने आखिर उनसे पूछा कि वे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं?

लालू यादव

हम रामलखनजी को जनता दल में आने का न्यौता दे रहे हों, ऐसी बात नहीं। यादव मतदाता तो पहले से ही जनता दल के साथ हैं। यादव वोटरों पर रामलखनजी का कोई बहुत प्रभाव भी नहीं। दरअसल, कांग्रेस में जो नेता निराश्रित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें जनता दल शरण देने को तैयार है।

बिहार की आबादी में यादवों का प्रतिशत १९.५ है। बिहार विधानसभा में यादव विधायकों की कुल संख्या ४७ है। इतनी संख्या में सदन में अन्य किसी जाति के विधायक नहीं हैं। २० यादव विधायक तो कांग्रेस के ही हैं। संप्रति, बिहार मंत्रिमंडल में काबीना स्तर के दो यादव मंत्री हैं, रामानंद यादव तथा रामजयपाल सिंह यादव। पर रामानंद व रामजयपाल का बिहार के यादव मतदाताओं पर कोई असर नहीं दिखता। इस लिहाज से तकरीबन २२ वर्षों से निरंतर सत्ता से वंचित रहने के बाद भी रामलखन सिंह यादव की ही थोड़ी-बहुत पकड़ बिहार के यादव मतों पर है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में रामलखन सिंह यादव को बस एक बार मंत्री की कुरसी नसीब हुई और उस मंत्री पद को लेकर वे अत्यंत विवादास्पद भी हुए। २ अक्तूबर, १९६३ को वे कृष्णबल्लभ सहाय के मंत्रिमंडल में शामिल किये गये थे और ५ मार्च, १९६७ को वे मंत्री पद से हटे। इसके बाद आज तक उन्हें मंत्री की कुरसी के दर्शन नहीं हो सके। १ अक्तूबर, १९६७ को गठित चर्चित अय्यर कमीशन की रिपोर्ट में टीएल वेंकटराम अय्यर ने मंत्री के रूप में रामलखन सिंह यादव की काफी खिचाई की थी। इसके बाद से रामलखन सिंह यादव कांग्रेस में तो रहे, पर कुरसीविहीन। श्रीमती गांधी उन्हें बिहार की राजनीति में महत्व तो देती थीं, पर सरकार में शामिल करने का संकेत उन्होंने भी कभी नहीं दिया। लिहाजा, कांग्रेस-एस और कांग्रेस-इ के विवाद के दिनों में रामलखन सिंह यादव कांग्रेस-एस की तरफ खिसक लिए थे। पर अंत में फिर श्रीमती गांधी की शरण में उन्हें लौटना पड़ा। कांग्रेस-इ में उनके आगमन के थोड़े ही दिनों बाद श्रीमती गांधी का निधन हो गया, पर राजीव गांधी ने रामलखन सिंह यादव का दिल रखने के लिए उनके बेटे प्रकाशचंद्र को बाढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिया। रामलखन सिंह यादव कभी मंत्री भी हो सकते हैं, इस फार्मूले पर राजनीतिक हलकों में सोचा जाना भी प्रायः बंद हो गया था। पर ११ मार्च, १९८९ को जब सत्येंद्रनारायण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो नियति ने रामलखन सिंह यादव के साथ एक अजीब मजाक किया। उस दिन राजभवन में शपथग्रहण समारोह के समय रामलखन सिंह यादव पीछे बैठे हुए थे। अचानक राजभवन के एक अधिकारी ने आकर उनसे अनुरोध किया कि उन्हें भी आज शपथ लेनी है, सो वे मंत्री-पद पर शपथ लेनेवाले लोगों की कतार में विराजें। प्रसन्नमन रामलखन सिंह यादव वहां जा बैठे। पर शपथग्रहण समारोह के ठीक पहले उनसे कहा गया कि वे मंत्री नहीं बनाये जा रहे हैं। राजभवन के अधिकारी ने गलतफहमी में उन्हें आगे लाकर बिठा दिया है। खचाखच भरे राजभवन में, अपने इस अपमान से घायल रामलखन सिंह यादव फौरन हाल से बाहर निकल आये। अगले ही दिन अखबारों में खबर छपी कि वे अस्पताल में भरती हैं। जाहिर है, वे राजभवन की घटना से बेहद आहत हुए थे। पर फिर उन्हें दिलासा दिलायी गयी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें शामिल कर पिछले अपमान का प्रतिकार अवश्य कर दिया जायेगा। स्वयं रामलखन भी सौ फीसदी आश्वस्त हो गये थे कि विस्तार में उनके साथ धोखा नहीं होगा। पर ताजा विस्तार में जब वे फिर छूट गये, तो उन्हें लगा मानो पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। लिहाजा, उन्होंने बयान दे डाला कि बिहार में कांग्रेस यादव मतों की उम्मीद अब छोड़ दे। रामलखन यादव को मनाने का कोई इंतजाम होता है या उनके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस पर अटकलें जारी हैं।

—विकास कुमार झा

एक बार फिर यू पी एस आई डी सी उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है

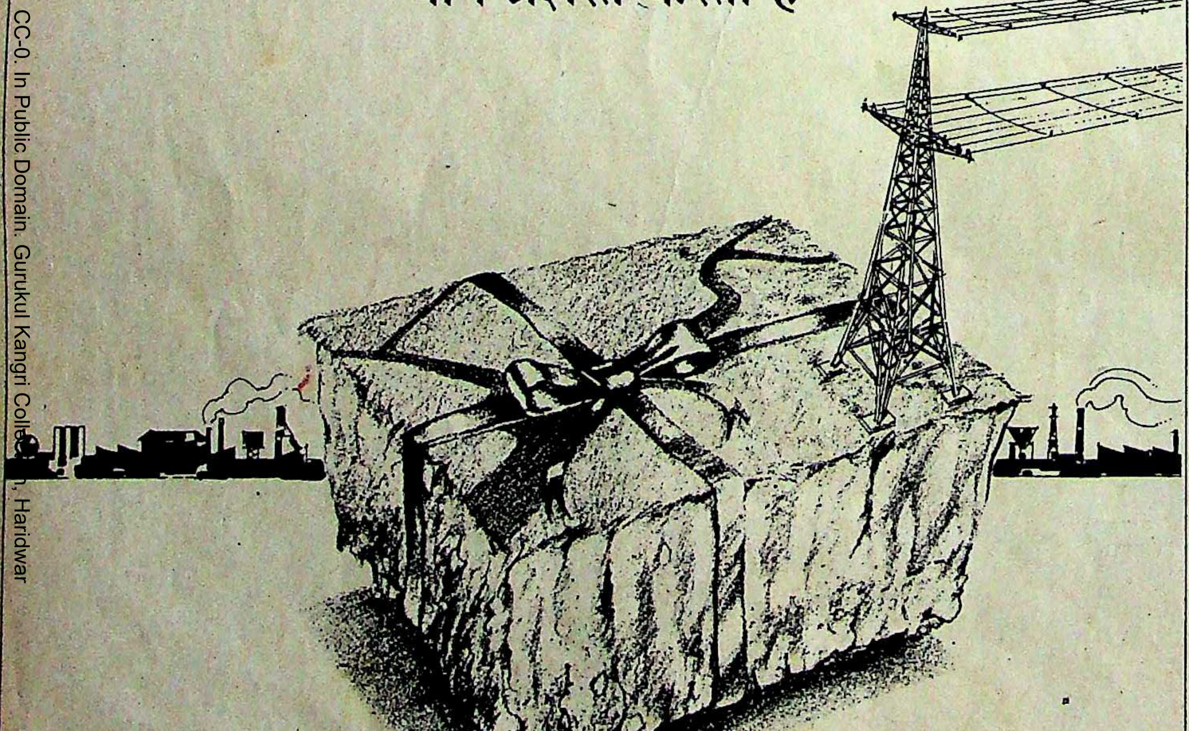

यू पी एस आई डी सी, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निगम, जिसने पिछले 26 वर्षों के दौरान पूरे राज्य में 112 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये हैं.

इन क्षेत्रों ने आकर्षित किया है बड़ी-बड़ी कंपनियों को, जैसे डी.सी.एम., टोयोटा, एस्कोर्ट्स, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, बी.एच.ई.एल., बी.ई.एल., एल एंड टी....और भी अनेक कंपनियां.

यू.पी.एस.आई.डी.सी. ने गाज़ियाबाद और बुलंदशहर जिलों में 16 औद्योगिक क्षेत्र कायम किये हैं. निगम की योजना है इन क्षेत्रों में विशाल औद्योगिक नगर बसाने की.

इन सभी नगरों में होंगी हर तरह की सुविधाएं.... आवास, व्यापारिक केन्द्र, बैंक, डाकघर, थाना, सिनेमा स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग आर्केड आदि.

यू.पी.एस.आई.डी.सी. अब एडवांस रजिस्ट्रेशन योजना प्रारंभ कर रहा है ताकि उद्यमी औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन की बुकिंग कर सकें और इस मामले में अनिश्चितता की कोई गुंजाइश ही न रहे.

वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में तुरंत आवंटन के लिये जमीन तो उपलब्ध है ही, इसके साथ ही बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों में बेहतरीन जगहों पर बन रहे नये औद्योगिक क्षेत्रों में भी बुकिंग का सुअवसर आपके पास है.

जो उद्यमी इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट आवंटित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

औद्योगिक/औद्योगिक आवास प्लॉट दिल्ली से केवल 16 से 40 किलोमीटर दूर

जनरल मैनेजर,
यू.पी.एस.
आई.डी.सी.
117/130,
सर्वोदय नगर
कानपुर-208005
(फोन: 218161-[illegible]5)

रीजनल मैनेजर, यू.पी.एस.आई.डी.सी.,
जी.डी.ए. बिल्डिंग (प्राइवेट बस स्टेंड),
गाजियाबाद, (फोनः 8-711103)

इसके अलावा आप नीचे बताये गये बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से प्रारंभ

upsidc

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान

जवाहरलाल नेहरू शताब्दी
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

फार्म निम्न बैंकों में उपलब्ध हैः ग्रिंडलेज बैंक पी.एल.सी. नई दिल्ली (10, संसद मार्ग) अमृतसर (गांधी बाजार), बंगलौर (मिशन रोड), बंबई (270, डी.एन. रोड), कलकत्ता (19, एन.एस. रोड), मद्रास (राजाजी सलाई), कानपुर (एम.जी.रोड), इलाहाबाद बैंक नई दिल्ली (पार्लियामेंट स्ट्रीट), आगरा (विलिंग रोड), अहमदाबाद (मस्कती मार्केट), अलवर (सिविल लाइंस), बरेली (सिविल लाइंस), बुलंदशहर (मेन), बड़ौदा (राजमहल रोड), चंडीगढ़ (सेक्टर 17 बी) देहरादून (गांधी बाजार), फरीदाबाद (हॉस्पीटल रोड), गाज़ियाबाद (नवयुग मार्केट), गोरखपुर (मेन), इंदौर (बाड़ा सर्राफा), जालंधर (सिटी), जमशेदपुर (बिस्तुपुर), जयपुर (एस.एम.एस. हाइवे), कोटा (झालावाड़ रोड), लखनऊ (हजरतगंज), लुधियाना (क्लॉक टॉवर), मेरठ (कैंट), मुरादाबाद (सिविल लाइंस), मुजफ्फरनगर (मेन), नौएडा (सैक्टर 12), पटना (गया रोड), पुणे (लक्ष्मी रोड), रोहतक (मेन), रांची (मेन), वाराणसी (चौक)

Nature at its purest

Presenting

Sneha

Butter, Ghee and instantly soluble Skimmed Milk Powder

Sneha. Dairy Products fresh as the early hours of the morning. Processed in one of the most sophisticated and modern dairy plants in India. Untouched by hand. Retaining all the flavour and purity of nature.

Sneha—It's nature's way of giving

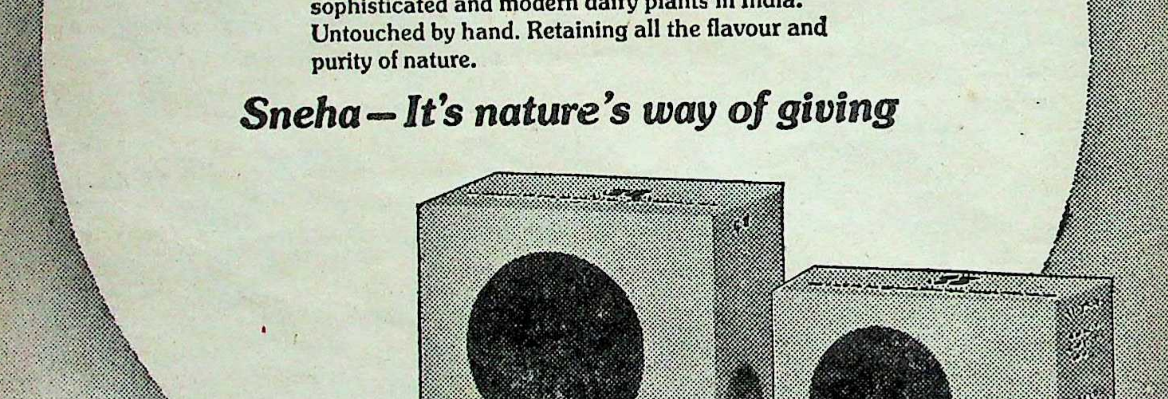
Sneha
PASTEURISED BUTTER
Sneha
PURE GHEE
Made in India by Indore Dugdha Sangh (Sahakari) Maryadit, Indore 453 771
Sneha
SKIMMED MILK POWDER
Spray Dried ☐ Instantly Soluble
Made in India by Indore Dugdha Sangh (Sahakari) Maryadit, Indore 453 771

Madhya Pradesh Dugdha Mahasangh (Sahakari) Maryadit

बेलगाम पुलिस

८ सितंबर '८९ को जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के सर मेनन हास्टल में घुसकर पुलिस बल ने बेकसूर छात्रों पर लाठियां क्यों तोड़ी ?

जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के चौथे सेमिस्टर की छात्रा कुमारी अंशु अग्रवाल, ८ सितंबर को अपनी सहेली नीलिमा सांघी की मोपेड की पिछली सीट पर बैठकर दोपहर में कालेज जा रही थीं कि 'साक्षरता अभियान' के संबंध में आयोजित रैली में भीड़ ले जाती हुई एक बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर से मोपेड चालक कुमारी नीलिमा सांघी और मोपेड तो फुटपाथ की ओर गिरीं, लेकिन अंशु अग्रवाल बस के पहिये के नीचे आ गयीं, फलस्वरूप उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया।

खबर मेडिकल कालेज पहुंची, तो क्रुद्ध छात्रों ने विरोधस्वरूप शहर की यातायात-व्यवस्था में लगी निजी क्षेत्र की मिनी बसों को रोकना प्रारंभ कर दिया। जिस बस से कुमारी अंशु अग्रवाल की मृत्यु हुई थी, उसका चालक बचाव के लिए बस लेकर करीबी थाने में पहुंच गया। दूसरी ओर क्रुद्ध छात्रों ने कालेज के सामने रोकी गयी कुछ मिनी बसों को आग लगा दी और राजस्थान पथ परिवहन की एक अन्य अनुबंधित बस के शीशे तोड़ दिये। मेडिकल कालेज तथा सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएच) के दोनों ओर की सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिये।

ताबड़तोड़ पिटाई : क्षेत्र के पुलिस थाना इंचार्ज नाथ सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह अपने पुलिस बल के साथ एसएमएच मेडिकल कालेज के एसके मेनन छात्रावास पहुंचे। पुलिस की सूचनाओं के अनुसार कथित उपद्रवी उक्त छात्रावास के ही थे। पुलिस बल जब छात्रावास में घुसने लगा, तो वहां नियुक्त चौकीदार बाबू लाल ने उन्हें रोकना चाहा। पुलिस बल उसी पर टूट पड़ा और उसे पीट-पीट कर जख्मी कर दिया। बाबू लाल ने मात्र अफसरों से यह पूछने की गुस्ताखी की थी कि उन्हें किसकी तलाश है और क्या उन्होंने छात्रावास के वार्डेन से अंदर घुसने की अनुमति ले ली है ?

उल्लेखनीय है कि किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा छात्रावास में बाहरी आदमी अथवा पुलिस संबंधित संस्था के अधिकारी की बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती। बहरहाल, चौकीदार के सवालों का जवाब पुलिस बल डंडों से देता हुआ दोमंजिले छात्रावास में घुसा और लगभग हर कमरे से छात्रों को घसीट-घसीटकर पीटा। उस समय ज्यादातर छात्र या तो अपने कमरों में सो रहे थे या अगले दिन होनेवाली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। घटना के चश्मदीद गवाह छात्र संजीव गौड़ के अनुसार, "पुलिस धड़धड़ाती हुई छात्रावास में घुसी। बंद कमरों के दरवाजे तोड़े, मारना-पीटना शुरू कर दिया। हम कह रहे थे कि अगर कोई बात है, तो हमें गिरफ्तार कर लो, पर उनका जवाब गाली और डंडे थे।" इस हादसे में कमर की हड्डी तुड़ा बैठे आशीष टंडन छठे सेमिस्टर के छात्र हैं जो छात्रावास के इकहत्तर नंबर के कमरे में हादसे के वक्त अपने दो साथियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। पुलिस ने जब हमला बोला, तो वे लोग दूसरे दरवाजे से भाग कर कमरा नं० ६९ में घुस गये। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दो छात्र तो दूसरी मंजिल से किसी तरह नीचे कूद गये, लेकिन आशीष नहीं कूद पाये। खिड़की के सामने खड़े आशीष को पुलिस के सिपाहियों ने डंडे मारे, आशीष का संतुलन बिगड़ा और वे दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। परिणामस्वरूप उनके कूल्हे की हड्डी में कई फ्रैक्चर हो गये। चौथे सेमिस्टर के छात्र शेवेंद्र गुप्ता के तो पांव ही तोड़ दिये। तीसरे वर्ष के छात्र दीपक शर्मा का हाथ टूटा है। सुनील बंसल, तरुण दीप सिंह तथा दीपक शर्मा सभी पुलिस दरिंदगी की कथा कह रहे थे। दीपक शर्मा की इस हादसे में रीढ़ की हड्डी चोटग्रस्त हुई है। न्यूरो सर्जन डा० धारकर बताते हैं कि यह चोट दीपक शर्मा को पक्षाघात तक ले जा सकती है, फिलवक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

पुलिस ने अपनी मारधाड़ का शिकार जहां मारीशस से अध्ययन के लिये आये छात्र राजन जीतन को बनाया, वहीं मलेशिया के छात्र संजीव जोशी को अपराधियों की तरह मार-मार कर

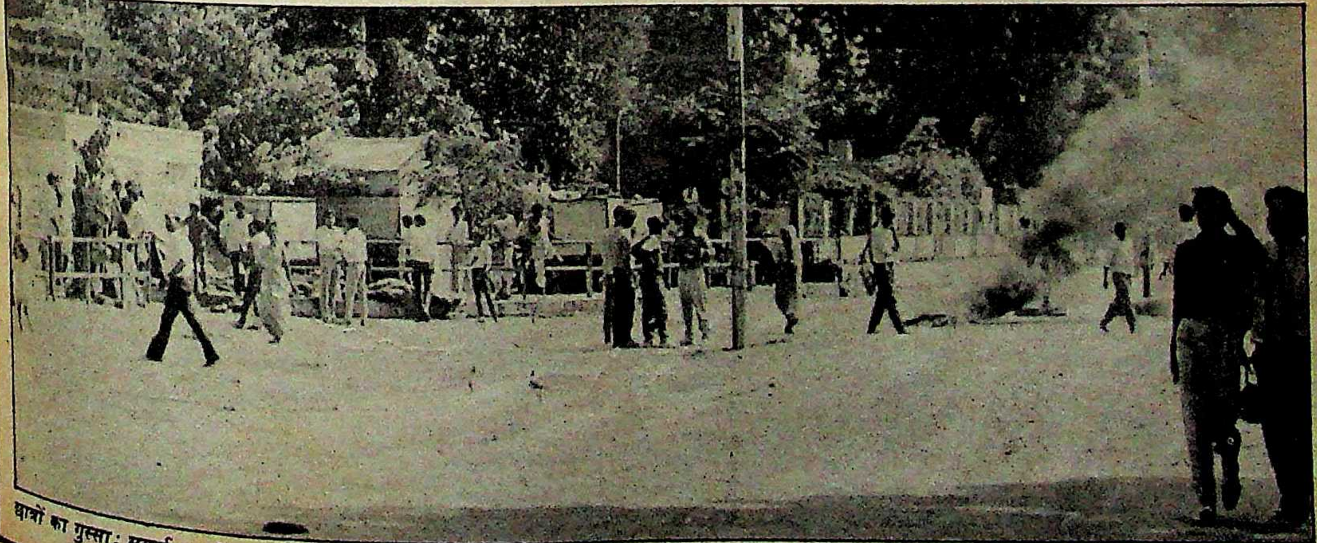

छात्रों का गुस्सा : सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सामने यातायात अवरोध

भुरता बना दिया। कुल पंद्रह छात्रों को अर्धनग्न अवस्था में पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी और पांच के हाथ-पांव तोड़ डाले।

'माया' प्रतिनिधि से छात्रावास के कार्यवाहक वार्डन डा० कर्णसिंह यादव ने कहा, "हम कानून को हाथ में लेने की बात का समर्थन नहीं करते, पर हम यह अधिकार भी पुलिस को नहीं देते कि हमसे अनुमति लिये बगैर वह हमारे छात्रावासों में घुसे। पुलिस अफसरों को हमारे वरिष्ठ डाक्टरों ने रोका, तो उन्हें अपमानित करने में भी पुलिस अधिकारी नहीं घबराये। हमारे सामने ही हमारे लड़कों का बाल पकड़-पकड़कर डंडे मारते हुए पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले गये। बेहद शर्मनाक दृश्य था।" डा० यादव ने घटना वाले दिन का विवरण देते हुए बताया, "शुक्रवार (८ सितंबर) को साढ़े तीन बजे अपराह्न में एक ओपन हार्ट सर्जरी करके घर लौटा था, तभी बदहवास से कुछ छात्र मेरे पास आये और बोले 'सर मेनन हास्टल में पुलिस घुस आयी है और बेरहमी से मारपीट कर रही है।' मैं तुरंत उनके साथ हास्टल पहुंचा, तो देखा कि थानेदार नाथ सिह तीस-चालीस पुलिस वालों के साथ छात्रों को डंडों से पीट रहे हैं और गर्दन पकड़-पकड़ कर पुलिस गाड़ी में ठूस रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बेहूदगी से मुझ पर बरस पड़े।" सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा० बीएम भंडारी भी पुलिस की इस कार्यवाही से बेहद क्षुब्ध थे।

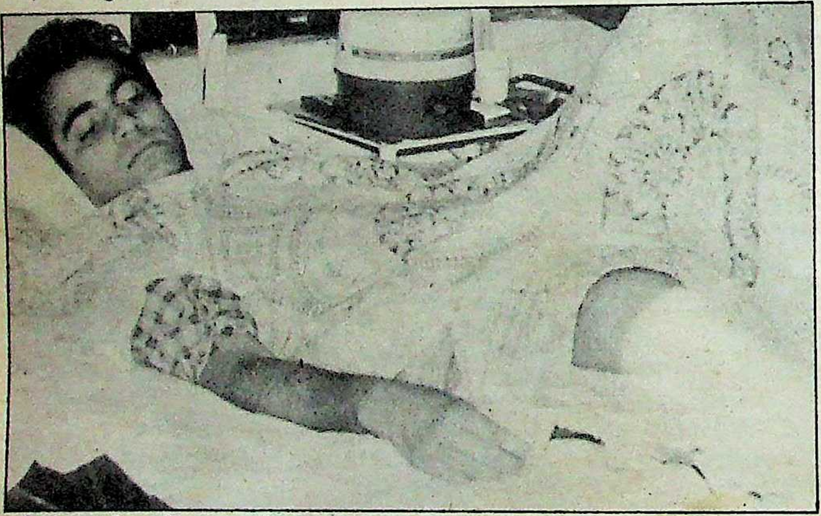

पुलिस ज्यादती का शिकार: आशीष टंडन

इस घटना के दिन राजधानी जयपुर में न तो मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे और न ही गृहमंत्री अशोक गहलोत। राज्य सरकार के आला लोग अगले दिन तक यहां नहीं पहुंच पाये थे। अगले दिन छात्रों ने घटना पर नाराजगी प्रकट करते हुए कालेज व अस्पताल के आसपास की सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिये जिससे आवागमन बंद हो गया। डाक्टरों ने अस्पताल में काम बंद कर दिया तथा प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों ने भी पुलिस दरिंदगी के खिलाफ हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। शनिवार की शाम को मुख्यमंत्री व गृहमंत्री अपने दौरे रद्द कर जयपुर लौटे। डाक्टरों के प्रतिनिधियों ने घटना का विवरण देते हुए मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिह तथा उनके सहयोगी थानेदार नाथ सिह व क्षेत्रीय थाना प्रभारी चैन सिह राजपुरोहित को तुरंत निलंबित किया जाये। साथ ही कुमारी अंशु अग्रवाल के परिवार को राहत दी जाये।

मुख्यमंत्री ने वार्ता के बाद सारा निर्णय. गृहमंत्री अशोक गहलोत पर छोड़ दिया। राज्य सरकार प्रारंभ में सारे मामले की जांच तक सहमत रही, फिर थानेदार नाथ सिह के निलंबन, पर राजी हुई। उधर मेडिकल छात्र अपनी मांगों में कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं थे। गृहमंत्री की समस्या यह बतायी जा रही थी कि अगर वह छात्रों की मांगें मान लेंगे, तो पुलिस बल कुंठित हो जायेगा। चूंकि अशोक गहलोत पूर्व में लापरवाही के लिए जिम्मेदार एक पुलिस अफसर का स्थानांतरण कर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके थे, लिहाजा वे शुरू में जोखिम लेने की अपेक्षा नहीं' की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने मामला गृहमंत्री पर छोड़ दिया। पर चतुर गृहमंत्री ने आगामी चुनावों में युवा मतों की अहमियत को देखते हुए रविवार की रात फैसला किया कि अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिह और थानेदार नाथ सिह पुलिस ज्यादती के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार ने इनके निलंबन व क्षेत्रीय थाना प्रभारी चैन सिह राजपुरोहित के तबादले के आदेशों के साथ पुलिस ज्यादती की जांच राजस्व मंडल के सदस्य से करवाने की घोषणा की। ज्यादती में घायल छात्रों की चिकित्सा व मृतक छात्रा के परिवार को मुआवजा देने का जिम्मा भी राज्य सरकार ने स्वीकार किया। तब जाकर मेडिकल कालेज में सारी स्थितियां सामान्य हुईं।

एक और मिसाल: पर पुलिस बल के चिंतन और व्यवहार में कोई फर्क नजर नहीं आता। जयपुर जिले की दौसा तहसील के ग्राम नागल राजावतान में पुलिस ज्यादती का ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है। उक्त गांव की एक ढाणी के निवासी रामजीलाल गुर्जर उर्फ फौजी के यहां इस वर्ष जून माह में चोरी हुई थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, तभी फौजी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को चोरी में शामिल लोगों के नाम बताये। फौजी ने अपने पास के गांव खवा के निवासी २८ वर्षीय बनवारी लाल हरिजन का नाम बता दिया। उसे गिरफ्तार कर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तब उसने बताया कि घटना के दिन वह अन्य गांव के बसंती हरिजन के यहां था। कथित अपराधी के साथ पुलिस का एक हवलदार और तीन सिपाही सचाई जानने के लिए उसे बसंती के गांव ले जा रहे थे। तभी पुलिस के अनुसार बनवारी ने रोडवेज की आती बस से टक्कर खाकर आत्महत्या कर ली। उधर चश्मदीद गांववालों का कहना है कि पहले मृतक को पीटा गया और बाद में उसे चलती बस से बाहर फेंका गया।

वस्तुस्थिति जानने वाले इन ग्रामीणों ने पुलिसवालों को पकड़कर सबक सिखाना चाहा, तो वे भाग कर थाने में घुस गये। ग्रामीणों की उत्तेजित भीड़ ने पुलिसवालों को कमरे में बंद कर दिया और थाने में आग लगा दी। बाद में पुलिस ने १९ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। उधर गांववालों ने अपना आरोप साबित करने के लिए मृतक के शव का पोस्टमार्टम फिर से कराने का आग्रह न्यायालय में किया । हालांकि पुलिस अपनी ओर से पोस्टमार्टम करवा चुकी थी और शव का अपने स्तर पर दाह करना चाहती थी। लेकिन मृतक के पिता, बसंती हरिजन व उसके रिश्तेदारों की बात न्यायालय ने माना और जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः पोस्टमार्टम करवाये जाने का आदेश दिया।

ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि प्रदेश की पुलिस मानवीय सोच से बहुत परे है और लोग उसकी ज्यादती के खिलाफ कानून हाथ में लेने लगे हैं। हालांकि राज्य के पुलिस महानिदेशक ज्ञान प्रकाश पिलानिया पुलिस थानों को सेवा-मंदिर बनाने की बात करते हैं, पर पुलिस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ शामिल नहीं किया गया जिससे सच उगलवाने व मानसिक संतुलन बनाये रखने का निर्देश मिलता हो। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि पुलिस व सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इन घटनाओं पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं होता।

छाया: गोपाल सगर

—ओम सैनी

राजस्थान में औद्योगिक विकास के कुछ कदम

राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में नाममात्र के लिए हुआ था। उस वक्त उद्योगों के नाम पर केवल सात सूती वस्त्र मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियां तथा इतनी ही चीनी मिलें थीं। स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध विकास से राजस्थान के औद्योगिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। प्रदेश की १९८८-८९ की वार्षिक योजना का आकार ७१० करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें उद्योग और खनिज पर ३५ करोड़ २२ लाख रुपए व्यय किये जा रहे हैं। आज राज्य में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में अनेक उपक्रम कार्यरत हैं।

प्रदेश में उत्पादित होनेवाली २७ मुख्य वस्तुओं में से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष १६ वस्तुओं में उत्पादन बढ़ा तथा ग्यारह में कम हुआ है। जिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, उनमें वस्त्र और सीमेंट उद्योग प्रमुख हैं।

वस्त्र उद्योग

भीलवाड़ा सिंथेटिक्स : यह दिलचस्प बात है कि राजस्थान में जिन १६ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है उनमें भीलवाड़ा जिला भी शामिल है। इस जिले के उद्योगपतियों ने पिछले कुछ सालों में ही वस्त्र उद्योग में अपनी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत पायी है। विशेष रूप से इस जिले का नाम सिंथेटिक उद्योगों के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्तमान में इस जिले में सिंथेटिक वस्त्र उत्पादनों की फैक्ट्रियां लगाने की होड़ लगी हुई है।

बहरहाल, इस होड़ में प्रमुखता हासिल है भीलवाड़ा उद्योग समूह की भीलवाड़ा सिंथेटिक को, जिसने राजस्थान को पहली बार अपने उत्पादन से देश में प्रसिद्ध कर दिया। इस उद्योग के विकास का श्रेय जाता है इसके युवा एवं कुशल प्रबंधक श्री आरएल नौलखा को जिनके निर्देशन में यह संस्थान निरंतर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।

हाल में इस संस्थान ने दस करोड़ की लागत से ३५८४ नये तकुए लगाये हैं। इनसे टेरीवूल का धागा बनने लगेगा और सितंबर माह में 'मेरीनो वूल' के मिश्रण से बना कपड़ा बाजार में आ जायेगा। संस्थान ने वर्ष १९८८ में ५२ लाख रुपए का उत्पादन निर्यात किया। इस उल्लेखनीय प्रगति के साथ-साथ देश में इस कंपनी के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए १५० डीलर्स विभिन्न शहरों और प्रदेशों में व्यवसायरत हैं।

संस्थान के प्रबंध संचालक श्री आरएल नौलखा का मानना है कि अगर भारत सरकार अपनी एक्साइज कर नीति की विसंगतियों को समाप्त कर दे, तो देशी उपभोक्ता को कपड़ा सस्ता मिल सकता है और निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। रेल व पथ परिवहन की असुविधा जहां अब भी इस उद्योग के विकास में बाधा बनी हुई है, वहीं दूरभाष व्यवस्था का यह आलम है कि आज भी भीलवाड़ा एसटीडी संचार व्यवस्था से नहीं जुड़ा है। श्री नौलखा राज्य सरकार द्वारा यार्न पर अन्य प्रदेशों से अधिक कर लिये जाने से भी परेशान हैं। वे चाहते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार को उद्योगों के विकास के लिए नीति बनाते समय उद्योगपति की दृष्टि से सोचना चाहिए।

भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड : प्रदेश में वर्ष १९८६ के मुकाबले कृत्रिम धागों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि २० से सौ प्रतिशत तक रही है। भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड के प्रबंध संचालक आरएन गुप्ता भीलवाड़ा में यार्न उद्योग के बढ़ावे के लिए राजस्थान वित्त निगम की तारीफ करते हैं। उनका मानना है कि भीलवाड़ा में सस्ते एवं अनुशासित मजदूरों के उत्पादन का ज्यादा बड़ा भाग स्थानीय वस्त्र मिलें कर लेती हैं। फिर भी उत्पादन अन्य प्रदेशों के माल के आगे बाजार में महंगा नजर आता है। वे बताते हैं कि यार्न उद्योग को राजस्थान में अपने उत्पादन पर तीन प्रतिशत बिक्री कर देना होता है, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों के उत्पादन पर बिक्री कर में छूट है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का विकसित तकनीकी से बना यार्न अन्य प्रदेशों के मुकाबले महंगा नजर आता है। बहरहाल, भीलवाड़ा स्पिनर्स का उत्पादन वस्त्र उद्योग में बहुत प्रसिद्ध है।

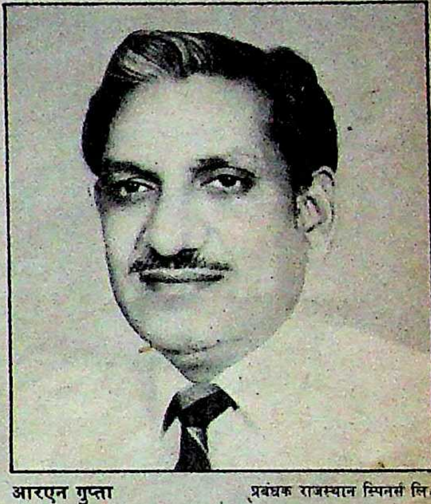

आरएन गुप्ता प्रबंधक राजस्थान स्पिनर्स लि०

जेके सीमेंट वर्क्स निंबाहेड़ा

राजस्थान में फिलवक्त सात सीमेंट फैक्टरियां सीमेंट उत्पादन कर रही हैं। इन फैक्टरियों में जेके सीमेंट वर्क्स निंबाहेड़ा में उत्पादन कार्य दिसंबर १९७४ से शुरू हुआ। कारखाने की प्रथम यूनिट को डेन मार्क के विश्व प्रसिद्ध सीमेंट विशेषज्ञ एफएफ स्मिथ के सहयोग से तैयार किया गया। यह यूनिट ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनानेवाली देश की पहली यूनिट थी। इस यूनिट को वर्ष १९७६-७७ में श्रेष्ठ उत्पादन (१२५%) के लिए पुरस्कृत किया गया। इस यूनिट की उत्पादन क्षमता ३.५६ लाख टन प्रति वर्ष रही है।

कारखाने में दूसरी यूनिट १९७९ में प्रारंभ हुई और उत्पादन क्षमता बढ़कर ७.२० लाख टन हो गयी। इस यूनिट के साथ कारखाने में प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल सिस्टम उपयोग में लाया जाने लगा। फिर राष्ट्रीय प्रगति प्लान के तहत फैक्ट्री में

राजस्थान :
गांव-गांव में रोजगार

जवाहर रोजगार योजना राज्य के देहाती इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का ठोस कार्यक्रम है। योजना के तहत दो लाख से अधिक व्यक्ति निर्माण-कार्यों में जुटे हैं। कार्यक्रम अपने पूरे वेग से जारी है।

ग्रामीण भारत में जिम्मेदार प्रशासन सच्चे पंचायत राज से ही कायम हो सकता है।

राजीव गांधी
प्रधानमंत्री

ग्राम हमारे सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के श्रम-क्षेत्र और कर्म-क्षेत्र बनें।

शिवचरण माथुर
मुख्यमंत्री

कार्यक्रम की विशेषताएं

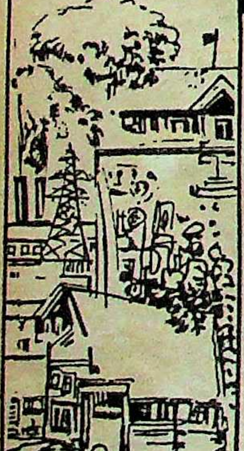

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के इस महायज्ञ पर लगभग 126 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान
- हर निर्धन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार
- महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रोजगार सुरक्षित
- अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता
- सभी पंचायतों को धनराशि का सीधा आवंटन
- मजदूरी के साथ सस्ती दरों पर गेहूं का वितरण

ग्राम की श्रम-शक्ति से ग्राम के पुनर्निर्माण की प्रभावी योजना

सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय, राजस्थान द्वारा प्रसारित

राजस्थान में फिलवक्त सात सीमेंट फैक्टरियां सीमेंट उत्पादन कर रही हैं। इन फैक्टरियों में जेके सीमेंट वर्क्स निंबाहेड़ा में उत्पादन कार्य दिसंबर १९७४ से शुरू हुआ। कारखाने की प्रथम यूनिट को डेन मार्क के विश्व प्रसिद्ध सीमेंट विशेषज्ञ एफएफ स्मिथ के सहयोग से तैयार किया गया। यह यूनिट ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनानेवाली देश की पहली यूनिट थी।

तीसरी यूनिट से उत्पादन वर्ष १९८२ में शुरू हुआ। तीसरी यूनिट प्रारंभ होने के साथ उत्पादन क्षमता ११.४० लाख टन प्रति वर्ष हो गयी। सन १९८७ में फैक्ट्री की उत्पादन गति एक सौ एक प्रतिशत थी जिसे प्रबंधक पुनः १२५% तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। फिलवक्त जेके सीमेंट निंबाहेड़ा की मासिक उत्पादन योजना एक लाख पचास हज़ार टन की है जो देश के श्रेष्ठ सीमेंट प्लांटों से अधिक है।

जेके सीमेंट वर्क्स, जेके सिंथेटिक्स लि० का सीमेंट डिवीजन है। इसके चेयरमैन गौरहरि सिंहानिया हैं जो अपने ग्रुप की बहूद्देशीय योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। निंबाहेड़ा स्थित सीमेंट कारखाने के निदेशक यदुपति सिंहानिया हैं जबकि महाप्रबंधक का जिम्मा निभाते हैं, कैलाश नाथ।

संचालकों ने फैक्ट्री की विद्युत आपूर्ति के लिए १५ मेगावाट का थरमल प्लांट और डीजल विद्युत उत्पादक यंत्र लगा रखे हैं। संचालकों का मानना है कि अगर राज्य सरकार का विद्युत मंडल नियमित विद्युत सप्लाई बनाये रखे, तो सीमेंट का उत्पादन मूल्य और कम हो सकता है। वैसे वर्ष १९८८ में विद्युत मंडल ने विद्युत सप्लाई सुचारु रखी है। बिक्री कर की विसंगति से यह संस्थान भी परेशान है।

उत्तर भारत में इस सीमेंट का उपभोग १६.९४ प्रतिशत है, जबकि इसे भारत के ७३ सीमेंट प्लांटों के उत्पादन से प्रतियोगिता करनी होती है।

इस संस्थान का श्रमिक नियोजित तरीके से अपने भविष्य के लिए आश्वस्त है। उसके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सारी सुविधाएं संस्थान की ओर से उपलब्ध हैं। संस्थान के संचालकों का मानना है कि उत्पादकता लाभ में वृद्धि करती है और यह वृद्धि संस्थान, श्रमिक व देश को संपन्न बनाती है।

राजस्थान आवासन मंडल

राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष श्रीराम गोटेवाला का कहना है कि 'अपना घर, अपनी छत, अपना आंगन' हर आदमी का सपना है और इसे पूरा करने के लिए राज्य में १९७० से छह बड़े नगरों में राजस्थान आवासन मंडल ने कार्य शुरू किया था। मंडल की यह योजना अब जिलों के कस्बों, तहसीलों, मसलन कोटपतली, आमेर, बांदीकुई, दौसा, शाहपुरा, नीम का थाना में भी लागू होने लगी है।

श्रीराम गोटेवाला अध्यक्ष राजस्थान आवासन मंडल

राजस्थान आवासन मंडल में अब तक एक लाख ५६ हजार लोगों ने आवास के लिए पंजीकरण करवाया है। इनमें से ८५ हजार आवेदकों को मकान दिये जा चुके हैं। लंबे समय से प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को शीघ्र मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान आवासन मंडल ने १९८९-९० में ४० हजार मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा पूर्व में जहां पंद्रह हजार मकान प्रति वर्ष बनाये जाते थे, अब वहां इस वर्ष अकेले जयपुर शहर में ही १५ हजार मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकानों के निर्माण एवं आवंटन को प्राथमिकता देने की दृष्टि से मंडल द्वारा इन आय वर्गों के लिए लगभग सत्तर प्रतिशत मकानों का निर्माण किया जाता है। इन वर्गों के आवेदकों से मंडल अपनी विशेष योजना 'कल्पतरु' में पंजीकरण राशि भी पचास प्रतिशत कम लेता है।

मंडल ने छोटी माहवारी बचत करनेवाले मंडल के पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिए अधिकतम ६ वर्ष में मकान प्राप्त करने के लिए 'कुबेर योजना' चला रखी है। इसी तरह 'कल्पतरु योजना' के तहत आवेदक की मृत्यु की स्थिति में परिवार को प्राथमिकता से तत्काल मकान व सामूहिक बीमा योजना सहित चार प्रकार के लाभ दिये जाते हैं। मंडल में व्यवसायिकों के लिए समूह पंजीकरण योजना भी विचाराधीन है। इसमें पचास या इससे अधिक लोगों को समूह मानकर उन्हें एक जगह आवास देने का प्रयास किया जायेगा।

राजस्थान आवासन मंडल में अब तक एक लाख ५६ हजार लोगों ने आवास के लिए पंजीकरण करवाया है। इनमें से ८५ हजार आवेदकों को मकान दिये जा चुके हैं। लंबे समय से प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को शीघ्र मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान आवासन मंडल ने १९८९-९० में ४० हजार मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण

राजस्थान में ऊर्जा के गैरपारंपरिक स्रोतों के समन्वित विकास हेतु २१ जनवरी, १९८५ में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन किया गया। इस अभिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नये ऊर्जा स्त्रोतों के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने सितंबर, १९८२ में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की अलग से स्थापना की है।

राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण ने इसी के तहत वर्ष १९८८ तक प्रदेश के ४१८ गांवों तथा ढाणियों में २९६७ सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें चार करोड़ रुपए व्यय कर लगवायी हैं। इस वर्ष के अंत तक एक हजार से अधिक ऐसी लाइटें १६७ गांवों में लगाने की योजना है। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिकरण ने १३० स्थानों पर सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पावर पैक लगाये हैं तथा दो सौ से ज्यादा सौर ऊर्जा से संचालित गर्म पानी के संयंत्र लगाये हैं। इसी ऊर्जा से काम करनेवाले पंद्रह हजार के लगभग चूल्हे अभिकरण बेच चुका है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अभिकरण द्वारा निर्मित सौ पवनचक्कियां इस वर्ष लगायी जा रही हैं।

अभिकरण रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन, गहरे पानी के पंप और अन्य ऐसी योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के प्रयास में है, जिससे ऊर्जा के मामले में गांव स्वावलंबी बन जायें।

—ओम सैनी

राजस्थान आवासन मण्डल

ज्योती नगर, भगवान दास रोड, जयपुर

कल्पतरु योजना

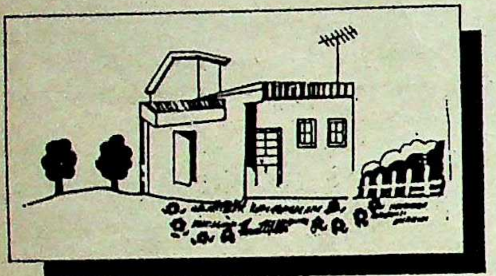

- इस योजना में कोई भी आवेदक किसी भी दिन पंजीकरण करा सकता है।
- इसमें आवेदक को ६ से १० वर्ष में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- जमा राशि पर ९ % चक्रवृद्धि ब्याज दिया जायेगा।
- आवेदक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को प्राथमिकता से मकान देने का प्रावधान है।

पारिजात योजना

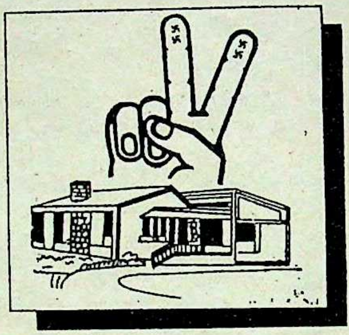

- राजस्थान आवासन मंडल की इस स्ववित्त पोषित योजना द्वारा आप आवास २ वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं।
- मकान की पूरी लागत २ वर्षों के दौरान ५ किश्तों में जमा करानी होगी।
- इस योजना में कोई भी पूर्व पंजीकृत आवेदक (कल्पतरु में पंजीकृत आवेदक भी) किसी भी दिन पंजीकरण करा सकता है।

कुबेर योजना

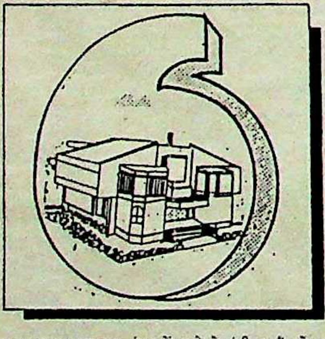

- यदि आप राजस्थान आवासन मंडल में पहले से पंजीकृत हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना में आवेदकों को २ वर्ष से ६ वर्ष में आवास प्राप्त कराया जायेगा।
- आवेदकों को प्रतिमाह निर्धारित किश्तें जमा करानी होंगी जिन पर उन्हें ९ % चक्रवृति ब्याज दिया जायेगा।

आवासनिधि योजना

- ऐसे उपभोक्ता जो अल्प बचत के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार रुपया जमा कराना चाहते हैं तथा प्रति माह किश्त देने के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिये मंडल ने आवास निधि योजना प्रारम्भ की है।
- जो व्यक्ति सामान्य पंजीकरण योजना में मकान लेने हेतु मंडल में पूर्व में पंजीकृत हैं, उनके द्वारा आवास निधि योजना में जमा राशि का समायोजन उनकी इच्छानुसार सीडमनी में कर दिया जावेगा।
- ऐसे आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार १०००/- रु० की गुणक रकम बचत के रूप में मंडल में जमा कराकर १२ % साधारण ब्याज प्रति वर्ष का लाभ उठा सकते हैं।

जवाहरलाल नेहरू जन्म शती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राज्य में इस वर्ष ४० हजार मकान बनाये जायेंगे। उसमें से १५ हजार मकान जयपुर में बनाये जाने का लक्ष्य है।
- नेहरू शताब्दी वर्ष में कलाकारों, शिल्पकारों, बीडी मजदूरों, बुनकरों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये ६ हजार मकान बनाये जायेंगे।
- अविवाहित/ तलाकशुदा अथवा विधवा अकेली महिलाओं के लिये इस वर्ष ही [illegible] है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
जन संपर्क अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
ज्योती नगर जयपुर
अथवा राजस्थान स्थित मण्डल के स्थानीय कार्यालय

B
The casual look!
BSL
Bhilwara®
SUITINGS

B J M
CHETAK
जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989
ASHOKA

नींव से शिखर तक शक्ति का प्रतीक

चेतक

भरोसेमन्द सीमेन्ट

BIRLA
JUTE & INDUSTRIES
LIMITED

बिड़ला सीमेंट वर्क्स
चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स
चित्तौड़गढ़-312021

मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च सभी
हमारी आस्था के केन्द्र हैं।
आइए हम सभी राष्ट्रीय एकता एवं
साम्प्रदायिक सद्भावना का पवित्र
संकल्प लें।

विक्रम सिमेंट का सुझाव भारत के बिल्डरो, कम करो ज़्यादा सिमेंट का इस्तेमाल

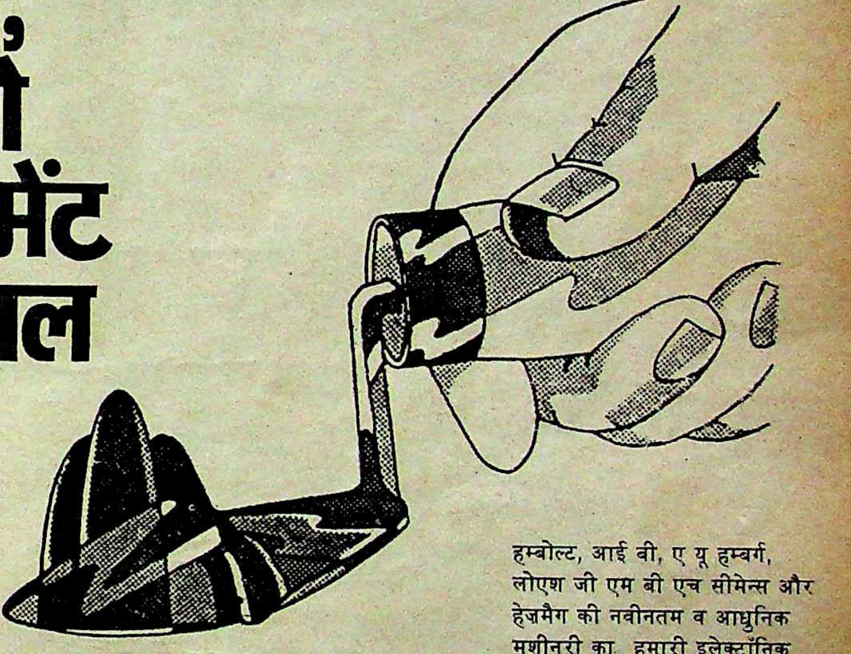

क्योंकि विक्रम सिमेंट का विश्वास है कि निर्माण में ज्यादा सिमेंट के इस्तेमाल से शक्ति नहीं आती. बल्कि शक्ति आती है उपयोग में आनेवाले सिमेंट की ऊंची क्वालिटी से.

इसीलिए विक्रम सिमेंट में ३ दिन की क्युरिंग पर लगभग ४०० कि०ग्रा०/सें०मी०^{२} की सुगठित शक्ति है. यह शक्ति आई एस आई की आवश्यक शर्त, यानी ३ दिन की क्युरिंग पर १६० कि०ग्रा०/सें०मी०^{२} से न सिर्फ बहुत अधिक है, बल्कि आज देश भर में उपलब्ध सभी सिमेंटों से अधिक है इसके दो अर्थ निकलते हैं

एक—जिस अनुपात में आप सिमेंट, रेत और एग्रीगेट (रोड़ी) अब इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही अनुपात में विक्रम द्वारा कहीं ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं.

दो—अब आप मिश्रण में सिमेंट का कम इस्तेमाल करके उतनी ही शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जितनी शक्ति अन्य सिमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करके मिलती है.

जहां तक शक्ति और दम-खम का संबध है, विक्रम विश्वास दिलाता है कि शुरू से अब तक, और आगे भी आप एक जैसे दम-खम वाला सिमेंट पाएंगे.

आपके लिए हम बेहतरीन क्वालिटी पेश करते हैं हम आभार मानते हैं कम्प्युटराइज्ड कन्ट्रोल रूम का, जो तैयारी के हर चरण में पूरी सावधानी बरतता है. साथ ही पश्चिम जर्मनी के के एच डी हम्बोल्ट, आई बी, ए यू हम्बर्ग, लोएश जी एम बी एच सीमेन्स और हेजमैग की नवीनतम व आधुनिक मशीनरी का हमारी इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन इतनी सही है कि आपके कार्यस्थल पर पहुंचने तक हर बोरी ५० कि०ग्रा० की ही रहेगी विक्रम सिमेंट के बेहतरीन सेटिंग समय तथा बहुत ही महीनपन ने इसे एक बेजोड़ सिमेंट बना दिया है जिस से आप अपने पैसों का सही मूल्य पा सकते हैं तो बेहतर यही है कि इसे ही अपनाया जाए

विक्रम सिमेंट

ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लि.

भूतपूर्व ग्वालिएर रेयॉन की एक इकाई

विक्रमनगर, पोस्ट ऑफिस, खोर (जावद), जिला, मन्दसौर, मध्य प्रदेश-४५८ ४७०
बम्बई कार्यालय: ८०८ डालामल हाउस, ८वी मंजिल, २०६, नरीमन पाइंट, बम्बई-४०० ०२१
फोन: २४५०७८-२४३५०७-२४१७८४. टेलेक्स: ०११-५४५५/५३६२ तार: VIKCEMENT

इतना मज़बूत कि कम में भी भरपूर दम

जानलेवा उपेक्षा

—ममता कालिया

पिछले दिनों इलाहाबाद का सबसे दर्दनाक, खौफनाक हादसा था—दो मेधावी, किशोर छात्रों का यमुना में अकस्मात डूब जाना। दोनों की उम्र थी अठारह वर्ष, दोनों ने बहुत अच्छे अंकों में विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण की थी, दोनों अपने घर परिवार के लाड़ले थे। अगर यह संयुक्त आत्महत्या होती, तो शायद उनके लिए मन इतना विचलित न होता। पर यह मात्र दुर्घटना थी और वह भी ऐसी, जिसे स्थगित या निरस्त किया जाना संभव था। दुर्घटना कुछ इस प्रकार थी। चार दोस्त शाम चार बजे घर से घूमने के इरादे से निकले। यमुना किनारे पहुंच कर उन्होंने नहाने की सोची। सबसे पहले एक लड़का पानी में उतरा। तह से बहुत दूर नहीं था वह। बखूबी अपने दोस्तों से बतिया रहा था और उन्हें भी नहाने के लिए प्रेरित कर रहा था। यकायक उसका पांव बालू में छुपे एक गहरे गड्ढे में धंस गया। अच्छा खासा स्वस्थ लड़का था वह। उसने एक पैर से संभलने की कोशिश की। लेकिन दूसरे पैर के धंसने से संतुलन बिगड़ गया। धंसते-धंसते वह चिल्लाया, "मैं डूब रहा हूं, मेरी मदद करो।" तट पर बैठे लड़कों में से दो ने समझा वह मजाक कर रहा है। लेकिन तीसरा तत्काल पानी में उतर गया। गड्ढे में धंसे हुए लड़के का हाथ पानी की सतह के ऊपर हिल रहा था। तीसरा लड़का लपक कर उस हाथ तक पहुंचा। उसे न यमुना की अकूत गहराई की फिक्र थी, न जानकारी। उसकी नजर में सिर्फ दोस्त का हिलता हुआ हाथ था। लेकिन सहारा देने को आतुर इस लड़के का पांव भी उसी गड्ढे में जा फंसा और वह भी आर्तनाद करने लगा, "बचाओ-बचाओ हम डूब रहे हैं, हेल्प अस, बिलीव मी।" तट पर बैठे बाकी दोस्त अब तक एकदम चौकन्ने हो गये। उन्होंने जोर-जोर से सहायता के लिए आवाज लगायी। शाम के उस वक्त तट निर्जन नहीं था। पास ही एक डोंगी थी। लेकिन डोंगी में बैठे सवार ने एकदम इनकार कर दिया। वह डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था। दोनों दोस्तों को कुछ मल्लाह दिखायी पड़े। वे उनके पास दौड़ गये। एक मल्लाह ने आराम से खैनी मलते हुए कहा, "गांठ में दाम धरे हो या सेंत में ही चिल्ला रहे हो।" लड़कों की सांस घबराहट से फूल रही थी, उन्होंने कहा, "जो कहोगे देंगे भई, पहले उन डूबते लड़कों को बचाओ। देखो उनके हाथ अभी भी पानी के ऊपर दिख रहे हैं।"

"बीस हजार लगेंगे, देबो" मल्लाह ने इतमीनान से कहा।

एक क्षण दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकते रह गये। यह रकम इतनी बड़ी थी, जितनी बड़ी उनकी उम्र भी नहीं थी। फिर उनमें से एक ने कहा, "ठीक है देंगे, तुम चलो तो।"

मल्लाह रस्सा लेने चल दिये। इस सब कार्रवाई में काफी समय लगा। फिर उन्होंने मेहनत से डूबे हुए लड़कों को ढूंढ़ निकाला। पेट का पानी पलटा गया, लेकिन बच्चों की श्वास नली में बालू जम गयी थी। दोनों ने वहीं यमुना तट पर प्राण त्याग दिये। अगले दिन नगर ने पढ़े अपने अखबार के तीसरे पृष्ठ पर एक साथ दो शोक-समाचार और यह खबर कि दो लड़कों की यमुना में नहाते वक्त जान चली गयी।

दुख की बात यही है कि यह खबर जहां समाप्त होती है, वहीं से शुरू होनी चाहिए। इस दुर्घटना में मानव-स्वभाव के महानतम और तुच्छतम पक्ष का एक साथ उद्घाटन हुआ है। एक तरफ एकदम कच्ची उम्र का ऐसा लड़का है जो न तैराक है न लड़ाक, वह अपने दोस्त को मुसीबत में फंसा देख कर लपक कर मदद के लिए जा पहुंचता है। दोस्ती का जज्बा उसके अंदर दुस्साहस की हद तक साहस पैदा कर देता है। वह एक क्षण को यह भी नहीं सोचता कि वह स्वयं संकट में फंस सकता है। उसे सिर्फ दोस्त का हिलता हाथ दिखायी देता है, उसके कान सिर्फ संकटग्रस्त दोस्त की पुकार सुन रहे हैं, किनारे बैठे और बौखलाए दोस्तों की चेतावनी उसे सुनायी नहीं देती। उसे अपनी सामर्थ्य पर इतना यकीन है कि वह पहुंचकर अभी अपने मित्र को वापस ले आयेगा। वह भंवर या गह्वर में फंस सकता है, यह बाद की बात है। उस एक क्षण में, आत्मघाती क्षण में वह मानवीय सरोकार का सबसे स्वर्णिम हस्ताक्षर बन बैठता है। दोस्ती की ऐसी मिसाल न दास्तानों में मिल सकती है न फसानों में, यह सिर्फ जिंदगी में मिल सकती है। इस दुर्लभ, दुर्दम साहस के आगे साहित्य, कला, इतिहास सब छोटे पड़ जाते हैं। कोई भी वीरता-चक्र इस साहस के लिए थोड़ा पड़ेगा।

दूसरी ओर, संकट की उस घड़ी में नदी तट पर बैठे, घूमते, बतियाते वे लोग हैं, जिनकी आंखें इस दुर्घटना को ऐसे देखती हैं जैसे भीड़ तमाशा देखती है या दर्शक फिल्म। वे लोग जानबूझ कर दुर्घटना स्थल से सरक जाते हैं, उनके हृदय उन डूबते लड़कों का आर्तनाद सुनकर हिलते नहीं हैं, उनके कदम, किनारे पर घबराहट से बौराये उन लड़कों की गुहार पर ठिठकते नहीं हैं जो चिल्लाये जा रहे हैं, "भाई साहब हमारे दो दोस्त पानी में डूब रहे हैं, वो देखो, उनके हाथ दिखायी दे रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए।" एक बार को हम सोच ले कि संभवतः वे इसलिए मदद नहीं करते, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। खैर फिर मदद की गुहार लगानेवाले लड़के वहां दिखायी दिये मल्लाहों के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं। मल्लाह तैरना जानते हैं, उनमें से कई गोताखोर का काम भी मेले के दिनों में करते आये हैं। वे नदी के चप्पे-चप्पे के जानकार हैं। उन्हें भी हवा में उठे हुए हाथ दिख रहे हैं। पर वे अपनी जगह से नहीं हिलते। वे पहले लड़कों की बदहवासी का जायका और जायजा लेते हैं, फिर विशुद्ध दुकानदारी पर उतर आते हैं। उनके सामने डूबते को बचाना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् डूबते से कमाना महत्वपूर्ण है। मजबूर लड़कों से सौदा पटा लेने पर ही वे पानी में उतरते हैं। उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं कि उनके विलंब के कारण दो दुर्लभ जाने चली गयीं, उन्होंने तो बस दाम के बल पर काम कर दिया।

शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध, जान लेनेवाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में अनेक धाराएं हैं, पर मुझे लगता है उसमें शायद ऐसी कोई कड़ी धारा नहीं, जिससे किसी की उपेक्षा के कारण घटित हुई मृत्यु में अपराधी को दंडित किया जाये। न जाने रोज कितने लोग डाक्टरों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण मौत के शिकार होते हैं, न जाने कितने छात्र, अध्यापकों की उपेक्षा के कारण अनुत्तीर्ण होते हैं और न जाने कितनी स्त्रियां घर-परिवार की उपेक्षा से हिस्टीरिया और न्यूरोसिस की शिकार होती हैं। इनमें से किसी भी क्षति के उत्तरदायी अपराधी को दंडित नहीं किया जाता। कानून केवल स्थूल अपराधों को अपनी गिनती में लेता है, जबकि सूक्ष्म, परोक्ष और शातिर अपराधों की गिनती समाज में कहीं बड़ी है। दुख से विचलित मन सोचता है कि क्या आधुनिक समय में वह शाश्वत सिद्धांत 'बचानेवाला मारनेवाले से बड़ा होता है' अब पलट कर 'मारनेवाला बचानेवाले से प्रबल होता है' हो जायेगा! ■

> **न जाने रोज कितने लोग डाक्टरों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण मौत के शिकार होते हैं, न जाने कितने छात्र, अध्यापकों की उपेक्षा के कारण अनुत्तीर्ण होते हैं और न जाने कितनी स्त्रियां घर-परिवार की उपेक्षा से हिस्टीरिया और न्यूरोसिस की शिकार होती हैं। इनमें से किसी भी क्षति के उत्तरदायित्व अपराधी को दंडित नहीं किया जाता।**

JET MAT
30 MATS
AN INVISIBLE PROTECTION FROM MOSQUITOES
MOSQUITO MAT

रात से लेकर सुबह तक
मच्छरों से रखे पूरी तरह सुरक्षित

जेट जानते है कि अपने नन्हें-मुन्ने से आपको कितना प्यार है.... कितना ख्याल है आपको अपने पूरे परिवार का, इसीलिए आप चाहते है इन सबको मिले एक स्वस्थ वातावरण और चैन की नींद. तभी तो जेट मॉस्किटो मैट आपको दिलाती है मच्छरों से संपूर्ण सुरक्षा और आप पूरे १० घंटे मीठे सपनों की नींद सो सकते है. जेट क्वालिटी पर पूरा भरोसा कर सकते है, क्योंकि इसके कुछ ठोस कारण है:

१. जेट मॉस्किटो मैट – दुनिया की जानी-मानी आधुनिक जापानी टेक्नालॉजी द्वारा ख़ास भारतीय परिस्थितियों के लिए बनायी गयी है.
२. कारखाने में ही मौजूद अति आधुनिक प्रयोगशाला में जेट मॉस्किटो मैट के हर बैच, यहां तक कि इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री की कड़ी जांच की जाती है.
३. सस्ती सेलोफ़िन पैकिंग में मैट के महत्त्वपूर्ण पदार्थों का बाष्पीकरण हो जाता है जबकि जेट मॉस्किटो मैट एल्यूमिनियम फॉइल में पैक होने के कारण इसके महत्त्वपूर्ण पदार्थ लम्बे समय तक ज्योंके त्यों बने रहते है.
४. इसकी मनमोहक खुशबू कमरे को तरो-ताज़गी से महकता रखती है.

इस तरह जेट है मच्छरों के खिलाफ़ न. १ सुरक्षा, आपके पैसों का दिलाए १०० % फायदा

जेट मॉस्किटो मैट

जनस्वास्थ्य के लिए समर्पित एक नाम

सोनिक इलेक्ट्रोकैम प्रा. लि.

[illegible] फोन: ६०५०७, ६८५७६.
केबल: जेट हाउस, टेलेक्स: ०७३५/४९० SONA IN.

Bidhan-SE-19 Hin

एक छोटा-सा कारण
एक सुरक्षित स्कूटर लेने के लिए
PIAGGIO

ज़रा कल्पना कीजिए. आप परिवार सहित स्कूटर पर जा रहे हैं। सड़क पर तेज़ रफ़्तार ट्रैफ़िक है। ऊबड़-खाबड़ रास्ता है। और आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्कूटर चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे में आपको चाहिए एक स्कूटर जो आपकी सुरक्षा के लिए ही बना हो। एक स्कूटर जो हर हालत में आपके इशारों का पालन करे।

एल एम एल – वैस्पा स्कूटर।

बेहतर स्थिरता, बेहतर संतुलन

किसी भी सड़क पर स्कूटर चलाते समय या मुड़ते समय कौन सी चीज़ आपकी सबसे अधिक सुरक्षा होती है? स्थिरता।

तभी तो एल एम एल का प्रत्येक स्कूटर एयरोडायनेमिक चेस्सी पर बनाया जाता है जिससे इसका संतुलन अन्य स्कूटरों से बेहतर है।

तुरंत रुके, फिसले नहीं

अक्सर ऐसा होता है। अचानक कोई साइकिल वाला सड़क पर आपके सामने आ जाता है या ट्रैफ़िक की बत्ती लाल हो जाती है और आपको तुरंत ब्रेक लगाने पड़ते हैं।

इस नाज़ुक मौके पर एल एम एल वैस्पा का डबल एक्शन सस्पैंशन और मूवेबल फ्रंट ब्रेक बैक प्लेट एक साथ काम करते हैं और स्कूटर को वहीं रोक देते हैं। बिना फिसले।

जोखिम से निकलने के लिए ज़ोरदार पिकअप

हम यह भी जानते हैं कि कभी कभी ट्रैफ़िक की खतरनाक स्थितियों से निकालने के लिए ज़ोरदार पिकअप की आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है।

इसी लिए एल एम एल वैस्पा के हर स्कूटर में ऐसा इंजिन है जो अपनी श्रेणी के किसी भी अन्य स्कूटर से अधिक शक्तिशाली है।

सुरक्षा से मुड़ने के लिए बिल्ट-इन इंडिकेटर

हमारा यह हमेशा विश्वास रहा है कि मुड़ते समय आपकी सुरक्षा इसी में है कि आपके दोनों हाथ हैंडिलबार पर रहें। तभी तो हमने अपने स्कूटरों पर आगे तथा पीछे दिशासूचक इंडिकेटर की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी, सरकार द्वारा इन्हें अनिवार्य बनाए जाने से पहले।

और हर बत्ती पर हमने लगाया है सालों-साल चलने वाला एक मज़बूत प्लास्टिक कवर।

रात को सुरक्षा के लिए एकसार रोशनी वाली हैडलाइट

अगर आप रात में कहीं भी जा रहें हो तब भी एल एम एल वेस्पा आपको सुरक्षित रखता है। इसमें लगी 12V मैग्नैटो रफ़्तार कम होने या सिर्फ़ इंजिन चलाने पर भी हैडलाइट और टेल-लाइट को धीमा पड़ने नहीं देती।

अपने एल एम एल वेस्पा पर सुरक्षित घर पहुँचिए

लाजवाब एन वी। और शानदार टी-5। एल एम एल वेस्पा आपके लिए प्रस्तुत करते हैं एक से एक मॉडल। कोई सा भी चुन लीजिए। हर एक इटली की पिआजियो कम्पनी की तकनीकी कुशलता की मिसाल है। हर एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार तैयार किया गया है। ताकि आप जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें।

ताज्जुब की बात है ना, कि हमारे छोटे-छोटे से बच्चे बड़े से बड़ा फैसला लेने में हमारी कितनी मदद करते हैं।

LML
vespa

बेहतर सुरक्षा. बेहतर डिज़ाइन.

LML
LIMITED

everest/d89/LML/213 hin

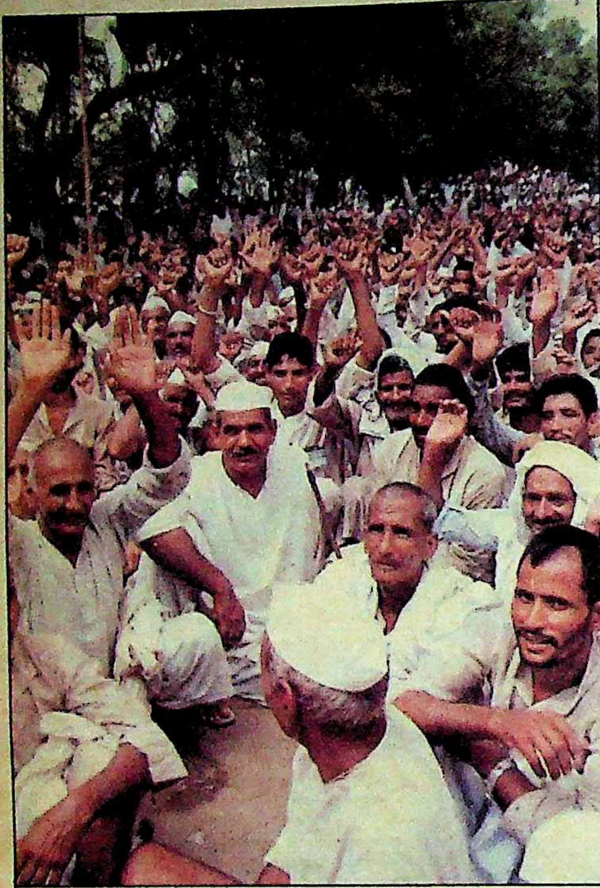

समझौता मंजूर : किसानों के बीच टिकैत

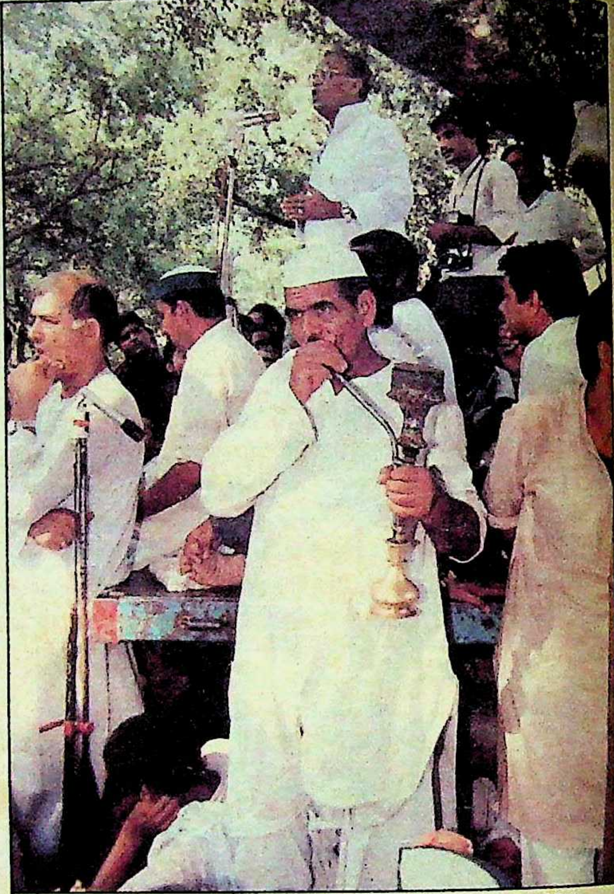

सरकार मेरे हुक्के पे : मंच पर नरेंद्र सिंह तथा बेपरवाह टिकैत (नीचे)

टिकैत से समझौता

क्या राजनीति में नये गुल खिलेंगे ?

ढाई वर्षों के दौरान कई आंदोलनों और १०६ किसानों की शहादत के बाद अब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गये हैं। कर्मूखेड़ी (मुजफ्फरनगर) के किसान आंदोलन की कमान संभालकर अचानक राजनीतिक सतह पर आये टिकैत ने अब तक कई आंदोलनों के जरिये यह दिखा दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका और उनकी भारतीय किसान युनियन (भाकियू) का कद राजनैतिक दलों से ऊंचा हैं। ४० दिन के धरने के बाद भोपा आंदोलन में समझौता भी टिकैत की शर्तों पर हुआ हैं। यह अलग बात है कि आम चुनाव के करीब १०० दिन पूर्व टिकैत को 'पटा' कर इंका नेतृत्व भी बहुत खुश है। जिस आंदोलन की आग को विपक्ष चुनाव तक जलाये रखना चाहता था, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अपने कूटनीतिक चातुर्य से उस आग को फिलहाल बुझाकर इंका के हाथ से खिसक रहे किसान मतों को बांधने की बहुत हद तक एक सफल कोशिश की है।

मांगें मंजूर : टिकैत की सबसे प्रमुख मांग बकाया बिजली-बिलों की माफी की थी। समझौते के तहत पूरे प्रदेश में किसानों के वर्ष १९८७-८८ के बकाये विद्युत शुल्क को माफ करने की शर्त मान ली गयी। इसके बाद के बकाये के बारे में सरकारी स्तर पर भाकियू के प्रतिनिधि की भागीदारी में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो यह तय करेगी कि शेष बकायों की किसान किस तरह अदायगी करेंगे। आंदोलन के दौरान जो किसान जेल गये, उन्हें रिहा करके किसानों पर कायम हुए मुकदमो को वापस ले लिया जायेगा। गांवों में महिलाओं के लिए शौचालयों की योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की जायेगी। समझौते में यह भी तय किया गया कि हर तीसरे मास महेंद्र सिंह टिकैत और प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के बीच किसानों की समस्याओं और उनके निदान को लेकर वार्ता होगी। भोपा आंदोलन मुख्यत: सीकरी गांव की नईमा के अपहरण और हत्या को लेकर शुरू हुआ था। सरकार ने इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की घोषणा की है। भोपा में १० सितंबर को किसानों के बीच सरकारी नुमाइंदे के रूप में प्रदेश के ऊर्जामंत्री नरेंद्र सिंह ने समझौते की घोषणा की और कहा कि नईमा के परिवार को जितनी रकम टिकैत कहेंगे, सरकार दे देगी। समझौते पर मुख्यमंत्री की ओर से ऊर्जामंत्री नरेंद्र सिंह तथा महेंद्र सिंह टिकैत की ओर से उनके सचिव हरपाल सिंह ने हस्ताक्षर किये। यह

समझौता भोपा आंदोलन के ३७ दिन बाद ७ सितंबर की रात पौने बारह बजे दिल्ली में हुआ।

समझौते की अंतर्कथा : इस चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार ने किसानों को मनाने का मन बना लिया था। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी किसी ऐसे सशक्त माध्यम की तलाश में थे, जो टिकैत और उनके बीच बातचीत करा सके। पहल के तौर पर उन्होंने पहले अपने मंत्रिमंडल के ही सदस्य मुजफ्फरनगर निवासी खाद्यमंत्री हुकुम सिंह को यह दायित्व सौंपा। इसकी एक वजह तो यह थी कि हुकुम सिंह स्थानीय नेता हैं, दूसरे उनके बड़े भाई मुख्तियार सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गूजरों के नेता हैं, जिनका टिकैत भी सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री की इस सोच को हुकुम सिंह के राजनीतिक स्वार्थ ने पूरा नहीं होने दिया। २६ अगस्त को हुकुम सिंह ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर महेंद्र सिंह टिकैत से बात तो की, लेकिन आंदोलन चलता रहे, इसलिए सुलह-सफाई को तरजीह नहीं दी। इसकी एक खास वजह यह थी कि उन्हीं के जिले से उनके प्रतिद्वंद्वी प्रदेश के गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमा इस आंदोलन के कारक थे। नईमा के अपहरण और हत्या में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप सईदुज्जमा पर लगा है। महेंद्र सिंह टिकैत का भी मानना है कि हुकुम सिंह ने जानबूझकर समझौते की बात आगे नहीं बढ़ने दी।

इस समझौते में मुजफ्फरनगर में तैनात गुप्तचर विभाग के एक निरीक्षक ने प्रमुख भूमिका निभायी। पर्दे के पीछे रहकर इसी निरीक्षक ने जानसठ के भाकियू अध्यक्ष कदम सिंह, स्वामी कल्याण देव, टिकैत के सचिव हरपाल सिंह और सहायक मांगे राम सहित मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक 'पश्चिम ज्योति' की संपादिका राजवीरी देवी को समझौते के इस प्रयास में मुख्यमंत्री और टिकैत का बिचौलिया बनाया। ११ अगस्त से इस प्रयास की शुरुआत हुई थी। राजवीरी देवी ने टिकैत से बात करने के बाद १४ अगस्त को लखनऊ आकर मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी से मंत्रणा की। २५ अगस्त को राजवीरी ने दिल्ली में पुनः मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें जानकारी दी कि टिकैत गुप्त वार्ता के लिए तैयार हैं। २ सितंबर को टिकैत किसान समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने दिल्ली गये थे। वे वहां अपने बहनोई सरदार सिंह वर्मा के ग्रेटर कैलाश पार्ट २ स्थित निवास पर ठहरे थे। उसी दिन सरदार सिंह वर्मा, राजवीरी देवी और हरपाल सिंह ने 'जंतर-मंतर' स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नारायणदत्त तिवारी से भेंट की। ३ सितंबर की शाम महेंद्र सिंह टिकैत और मुख्यमंत्री की लगभग ५ घंटे तक गुप्त वार्ता चली। इसी दौरान शीला दीक्षित ने भी वहां पहुंचकर गुफ्तगू की। सभी शर्तें उसी रात तय हो गयी थीं, किंतु समझौते में गोलमोल भाषा का प्रयोग होने के कारण टिकैत ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने सुलह-सफाई के लिए ऊर्जामंत्री नरेंद्र सिंह को अधिकृत कर दिया, तो टिकैत ने भी अपनी अहमियत बनाये रखने के लिए अपने सचिव हरपाल सिंह को अधिकृत किया। आखिरकार ७ सितंबर की रात पौने बारह बजे समझौता हो गया।

संपर्क-सूत्र : हरपाल सिंह

मुख्यमंत्री ने इस समझौते में टिकैत के नाजुक रिश्ते को भी अपने चातुर्य से भुनाया। टिकैत के बहनोई सरदार सिंह वर्मा की बिजली के तार और अन्य उपकरण बनाने की फैक्ट्री है। कहते हैं, इस समझौते के एवज में वर्मा को विद्युत विभाग में बड़ी सप्लाई देने का वायदा किया गया है।

टिकैत की ताकत : चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में शून्यता आ गयी थी। अचानक आये इस खालीपन को भरने की कोशिश उनके पुत्र अजीत सिंह ने जरूर की पर, पश्चिमी सभ्यता में पले-बढ़े अजीत सिंह, गांव के ठेठ जाट किसानों को रास नहीं आये। ठीक ऐसे वक्त में महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता के रूप में सामने आये। चौधरी चरण सिंह के चरित्र से टिकैत का चरित्र बिलकुल भिन्न है। चरण सिंह राजनीतिक दल के झंडे के नीचे किसानों की रहनुमाई करते थे, लेकिन टिकैत ने मौजूदा राजनीति का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए अभिजात्य वर्ग के लोगों के नेतृत्व को नकार दिया। उन्होंने पंचायत व्यवस्था को अपना आधार बनाकर किसान हितों की लड़ाई शुरू की। टिकैत का यह तेवर किसानों को भा गया। नतीजतन ढाई वर्ष की छोटी अवधि में ही टिकैत न केवल सर्वमान्य किसान नेता बन गये, बल्कि राजनीतिक न होते हुए भी राजनीतिक समीकरणों की धुरी बन गये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग १७ संसदीय तथा ५६ विधानसभा सीटों पर काबिज होने के लिए सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां टिकैत और उनकी यूनियन के समर्थन की मोहताज हैं। टिकैत की ताकत इस बात से आंकी जा सकती है कि देश के दूसरे स्थापित किसान नेताओं को टिकैत से झुककर हाथ मिलाना पड़ा है। शामली के प्रथम किसान आंदोलन के नेता टिकैत का सान्निध्य पाने के लिए देश के अन्य किसान नेता अब अखिल भारतीय स्तर का एक किसान संगठन बनाने को प्रयत्नशील हैं।

राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव वर्ष में भारतीय किसान यूनियन और टिकैत को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। यही कारण है कि जहां एक तरफ इंका हाईकमान की ओर से बलराम जाखड़ और राजेश पायलट से लेकर मुख्यमंत्री तक टिकैत को साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के वीपी सिंह, देवीलाल और अजीत सिंह जैसे दिग्गज टिकैत को 'पटाने' में लगे हैं। हालत यह है कि जिस इंका के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने ८ अगस्त को कैराना (मुजफ्फरनगर) की इंका रैली में टिकैत को 'डकैत' कहा था, उसी इंका को ठीक एक माह बाद टिकैत को ससम्मान बुलाकर उन्हीं की शर्तों पर समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा।

चुनावी परिप्रेक्ष्य : भारतीय किसान यूनियन के प्रभाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिलहाल ११ जिले हैं। इन जिलों में १७ संसदीय सीटों पर टिकैत का रुख निर्णायक साबित होगा। बागपत की परंपरागत सीट लोकदल के पास है (यह चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद से अभी तक रिक्त है)। शेष १६ सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस तरह ११ जिलों में विधानसभा की ९५ सीटों में ५६ भाकियू के प्रभाव क्षेत्र में हैं। इस समय इनमें से ३० कांग्रेस, २२ लोकदल, २ भाजपा और २ निर्दलीय के पास हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता अपनी इन सीटों को बचाने की है। कांग्रेस इस तथ्य से सचेत है कि तब के चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति काफी बदली हुई है। तब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जनमानस में इंका के प्रति उपजी सहानुभूति तो थी ही, भारतीय किसान यूनियन का भी उदय नहीं हुआ था। भाकियू का रुझान शुरू से ही चौधरी चरण सिंह की पार्टी की ओर रहा है। इस यूनियन की बुनियाद जाट किसानों की खाप व्यवस्था है। यही वजह है कि इंकाइयों द्वारा इसे जाटों का संगठन प्रचारित करते हुए अन्य जाति के किसानों को भरमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस क्षेत्र के इंका नेता यह भी स्वीकार करते हैं कि भाकियू की भूमिका आगामी चुनाव में निर्णायक होगी। मुजफ्फरनगरवासी प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री हुकुम सिंह ने 'माया' से बातचीत के दौरान स्वीकारा कि महेंद्र सिंह टिकैत के समर्थन के बिना किसी भी प्रत्याशी के चुनाव जीतने में संशय है।

१९८४ के संसदीय चुनाव में भाकियू के प्रभाववाले क्षेत्रों की १७ में से १६ सीटों पर इंका ने कब्जा किया था। लोकदल दूसरे नंबर पर रहा

था। बदली हुई परिस्थितियों में यदि भाकियू का झुकाव जनतादल की ओर हुआ, तो इस बार नतीजे पलट सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जहां एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने समझौता करके किसानों के बदलते रुख को थामा है, वहीं अजीत सिंह ने गांव-गांव का दौरा करना शुरू कर दिया है।

भाकियू की अदरूनी जानकारी रखनेवाले बताते हैं कि इस यूनियन से संबद्ध किसान गैरराजनीतिक तौर पर तो महेंद्र सिह टिकैत के फतवे को मान लेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि टिकैत किसी दल विशेष को समर्थन देने की घोषणा करते हैं, तो उनकी किरकिरी हो जायेगी। इस तथ्य को राजनीतिक स्तर पर लड़े गये इस बार के ब्लाक प्रमुखों के चुनाव से समझा जा सकता है। जिस मुजफ्फरनगर में भाकियू का सर्वाधिक प्रभाव और मुख्यालय है, वहां १४ में केवल दो ब्लाक—जानसठ और भोपा—से भाकियू से संबद्ध वीरेंद्र सिंह और ब्रह्म सिंह विजयी हो सके। दोनों जनतादल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यह सब जानते हैं।

सरकार टिकैत की गिरफ्त में

भाकियू का असरदार जाट तबका भी राजनीतिक तौर पर चौधरी टिकैत की किसी घोषणा का पाबंद नहीं है। इस वर्ग में स्व० चरण सिंह की जातिगत तस्वीर अब भी समायी हुई है। उनके पुत्र अजीत सिंह से इस वर्ग का मोहभंग हो गया है, ऐसी बात नहीं है। इसी २९ मई को स्व० चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली के किसान घाट पर और अजीत सिंह ने बड़ौत में अपनी-अपनी जोरदार रैलियों का आयोजन किया था। हैसियत की यह लागडाट शुद्ध रूप से जातीय आधार पर विरासत की लड़ाई थी। टिकैत का आयोजन गैरराजनैतिक था, जबकि अजीत सिंह अपने पिता के जातीय मतों को अंदाजना चाहते थे। अजीत सिंह के इस राजनीतिक दृष्टिकोण को भांप कर भी दिल्ली के किसान घाट की अपेक्षा बड़ौत की किसान रैली में ज्यादा भीड़ थी। इसी से उत्साहित होकर अजीत सिंह ने २५ जून को सिसौली से २० किलोमीटर दूर शामली में अपनी सफल जनसभा की। इसी के बाद बुलंद हौसले के साथ अजीत सिंह ने अगस्त मास में मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के गांवों की परिक्रमा की। उनके इस राजनीतिक हौसले को पस्त करने की ही नीयत से महेंद्र सिंह टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में एक पंचायत में घोषणा कर दी कि अजीत सिंह को बालियान खाप (जिसमें टिकैत चौधरी हैं) के गांवों में नहीं घुसने दिया जायेगा। बावजूद इस घोषणा के ३ तथा ५ अगस्त को अजीत सिंह ने बालियान और गठवाल खाप के जाट गांवों का दौरा किया। उनका भरपूर स्वागत हुआ। भोपा आंदोलन में भी वे शामिल हुए। इसी के बाद टिकैत का सुर बदला और उन्होंने अजीत सिंह को ईमानदार और शरीफ व्यक्ति कहा। ठीक इसी समय जब अजीत सिंह गांव-गांव घूम कर अपने प्रभाव की थाह ले रहे थे, शामली में आयोजित इंका की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नवी आजाद ने टिकैत को 'डकैत' कह कर भाकियू के सत्तापक्ष से विमुख होने की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। यह तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी की सूझ-बूझ थी कि उन्होंने समय रहते भाकियू और उसके नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ सम्मान समझौता कर उन्हें मना लिया।

जातीय आधार: इस संभावना को झुठलाया नहीं जा सकता कि भाकियू के बढ़ते प्रभाव के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीयता ही चुनाव की धुरी होगी। भोपा आंदोलन में शिरकत करनेवाले एक गांव के गैर जाट प्रधान (नाम न छापने का अनुरोध) का कहना था, "भाकियू में गैरजाटों की भागीदारी भी अहम मायने रखती है, किंतु इसे उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं। यहां जाट सबल हैं, जाहिर है मजबूरों और गांव के निर्बल किसानों में उनके कहे को टालने की हिम्मत नहीं है।" यूनियन के इस सबल तबके की लोगों से बद सलूकी और हठधर्मी हर आंदोलन में देखी जा सकती है। यही कारण है, कि यूनियन से संबद्ध रहते हुए भी अन्य जाति के किसान अंदर-अंदर जाटों से खार खाये हुए हैं। यह तथ्य बताते हैं कि चुनाव के समय गैरजाटों के मत उन्हें नहीं मिलेंगे, जिन्हें जाटों का समर्थन प्राप्त होगा। मिसाल के तौर पर भाकियू के गढ़ मुजफ्फरनगर को लिया जा सकता है। इस जिले के निर्विवाद व स्वच्छ छविवाले इंका नेता महेंद्रप्रकाश डागा जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे बताते हैं, "महेंन्द्र सिह टिकैत और उनकी किसान यूनियन की चुनावी अहमियत को

साक्षात्कार: महेंद्र सिंह टिकैत

हमारे पास वह सब है जो चुनाव के लिए जरूरी है

***माया :** क्या इस समझौते से आप सहमत हैं?*

टिकैत : *सहमत नहीं होंगे, तो हम किसान और कर भी क्या सकते हैं? हमारी तो मजबूरी है। चुनाव का समय न होता, तो शायद हमें और भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती। सरकार सबल है और हम निर्बल, ऐसे में अपनी मनमर्जी से सरकार जो समझौता करेगी, हमें तो मानना ही पड़ेगा।*

माया : लेकिन यह समझौता तो आपकी शर्तों पर हुआ है?

टिकैत : *कैसी शर्त? हमने अपने अधिकार मांगे। यह समझौता करके सरकार ने किसानों पर कोई अहसान नहीं किया है। हम ढाई वर्ष से अपने कई अधिकारों के लिए लड़-मर रहे हैं। पहले क्यों नहीं सरकार ने हमारी शर्तों को परखा? हम अभी अपने कई अधिकारों से वंचित हैं। हमारी शर्त मानने का सिर्फ प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग सोचें कि शर्तों पर समझौता होने के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं हैं।*

माया : आपके आंदोलनों में हिंसा एक नियति-सी बनती जा रही है। ऐसा क्यों?

टिकैत : *भाकियू एक निहत्था संगठन है। अहिंसा के बल पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। गांधीजी ने उसी अहिंसा की बदौलत आजादी हासिल करायी थी, लेकिन क्या तब लोग शहीद नहीं हुए थे। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। सरकार लाठी और रायफलों के बल पर किसान एकता को कुचलना चाहती है। हमें यह भी दिखाना है कि किसान शक्ति सर्वोपरि है। इसी वजह से खाकी वर्दीधारियों और लंगोटीधारी किसानों में कभी-कभी शक्ति-परीक्षण हो जाता है।*

नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जाटवादिता ही इस यूनियन की बुनियाद है, यह भी एक सचाई है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाये, तो जब-जब जाटवाद बढ़ा है, खुद जाटों को नुकसान उठाना पड़ा है। १९७१ में इसी जाटवाद के चलते चौधरी चरण सिंह को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा था।"

१९७१ में कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में चौधरी चरण सिंह को ५२ हजार मतों से हरानेवाले वयोवृद्ध विजयपाल सिंह में अब भी वही राजनीतिक दमखम है। १९७१ जैसी परिस्थिति को परखकर ही वे इस बार मुजफ्फरनगर की उसी संसदीय सीट की उम्मीदवारी की आस लगाये हैं, जहां से उन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेता का दंभ तोड़ा था। विजयपाल सिंह बड़ी गहराई से चुनाव में भाकियू की अहमियत का विश्लेक्षण करते हैं, "भाकियू की ताकत जाट किसानों के बल पर है। जाटों की सबलता और हेकड़ी के कारण गांव का आम किसान भयभीत है। निर्बल किसान इनके दबदबे के कारण इस बार भी अपना मत नहीं डाल पायेंगे। इस बार जमकर मतदान-केद्रों पर कब्जा होगा।"

जाटों में सम्मानित चौधरी बलवंत सिंह भी बिरादरी के ओहदेदार हैं। विधायक रह चुके वयोवृद्ध बलवंत सिंह मानते हैं कि भाकियू मुख्यत: जाटों का संगठन है। वे बताते हैं, "पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कभी जमींदार नहीं रहे। इस क्षेत्र में वैश्यों का प्रभाव रहा है, जो अब उतना नहीं है। जाटों में १९५२ के बाद से राजनीतिक रूप से जागृति आयी जो चौधरी चरण सिंह की देन थी। चरण सिंह हर वर्ग के किसानों की रहनुमाई करते थे, लेकिन उनकी विरासत हासिल करने का प्रयास करनेवाले महेंद्र सिंह टिकैत में वह बात नहीं है।" उनका कहना है, "किसानों के प्रति समझौते की नरमी बरत कर कांग्रेस ने न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में अपने प्रति उपजे विरोध को सुलटाया है, वरन पूरे प्रदेश के किसानों का रुख अपनी ओर मोड़ा है। इसके बेहतर नतीजे होंगे।"

टिकैत की महत्वाकांक्षा : महेंद्र सिंह टिकैत की महत्वाकांक्षा भी राजनीति के दर्पण में साफ़ झलकती है। भाकियू नेता का सान्निध्य पाने की राजनीतिक दलों में बढ़ती लालसा को परख कर टिकैत चुनाव में अपने समर्थक उम्मीदवार को टिकट दिलाने की शर्त रख सकते हैं। चुनाव के १५ दिन पूर्व अपना निर्णय जाहिर करने की उनकी घोषणा इसी सौदेबाजी की चाल मानी जा रही है। वे खुद भी भाकियू से संबद्ध सक्रिय लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतार सकते हैं, यह संकेत उनके इस कथन में मिलता है, "हमारे पास वह सब कुछ है जो एक राजनीतिक दल के पास होना चाहिए। पैसा है, झंडा है, चुनाव चिह्न है और सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता हैं।" टिकैत के गांव सिसौली में बने किसान भवन की भव्यता और उसमें पांच सितारा होटलों जैसी तरण ताल की आधुनिकता को देखिये, जिसमें बकौल भाकियू के सचिव हरपाल सिंह, "१६ लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी काम जारी है।" हरपाल सिंह बताते हैं, "भाकियू के मुख्यालय सिसौली के केंद्रीय कार्यालय में जल रही अमर ज्योति के पात्र में हमेशा १४ किलो देशी घी भरा रहता है। भोपा आंदोलन तक इस ज्योति में लगभग ११ कुंटल घी जल चुका है। गरीब किसानों की सहायता और आंदोलनों की व्यवस्था के लिए एक अलग कोष है। हमारा कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें एक लाख रुपये से कम की रकम दानस्वरूप न उतरी हो। बोट क्लब के धरने के समय चौधरी टिकैत २२ बार नोटों-सिक्कों से तुले थे। उस समय उनका वजन ८ हजार रुपए के बराबर था, अब तो और बढ़ गया है।"

इंका को फायदा : बलवंत सिंह

उम्मीदवारी की आशा : विजयपाल सिंह

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल द्वारा ट्रांसफार्मरों के लिए दी गयी तीन लाख रुपए की थैली भाकियू ने थाम ली। यह इस बात का संकेत था कि भाकियू का झुकाव जनतादल और मुख्यत: जाटों की ओर था। अब हुए समझौते में यह बात भी शामिल है कि यह रकम मय ब्याज के उप्र सरकार भाकियू की मार्फत देवीलाल को वापस कर देगी। एक समझौते के बाद टिकैत द्वारा चलाया जा रहा किसान आंदोलन थम जायेगा, ऐसी उम्मीद नहीं, क्योंकि जबतक मुद्दे रहेंगे तब तक टिकैत का महत्व बना रहेगा। इसी वजह से इस समझौते के बाद भी टिकैत ने किसानों के अन्य बकायों की माफी को लेकर असहयोग आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। बहरहाल, इस समझौते ने किसानों की मन:स्थिति बदली है।

—सुरेश द्विवेदी

छाया : राजेंद्र कुमार

माया : आनेवाले चुनाव में भारतीय किसान यूनियन का समर्थन सभी राजनीतिक दल हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में आप और आपकी किसान यूनियन क्या भूमिका अदा करेगी?

टिकैत : हम गरीबों की क्या भूमिका? यदि किसानों का इतना ही महत्व समझा जाता, तो हमें इतने दिनों तक आंदोलनों और बलिदानों की नौबत से न गुजरना पड़ता। सरकार यदि हम किसानों की समस्या का समाधान कर दे, तो हम अपने घर बैठ जायेंगे। हम तो चाहते हैं कि चुनाव ही न हो। हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और किसी को रोकेंगे भी नहीं। हां, यदि हम किसानों की सारी समस्याओं का निदान न हुआ, तो हम विचार करेंगे कि चुनाव में हमें क्या करना है। चुनाव के १५ दिन पहले ही कोई घोषणा करेंगे।

माया : अभी तक भाकियू की संसद और विधानसभा में भागीदारी नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि चुनाव के जरिये निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से जीतकर संसद और विधानसभा में अपने हक की आवाज उठायी जाये?

टिकैत : बात तो ठीक है, लेकिन चुनाव में हिस्सा लेने से हम अपने को गैरराजनीतिक नहीं कह सकते। वैसे राजनीति में हमारे आने में देर भी नहीं लगेगी। हमारे पास अपना झंडा है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, 'खेत जोतता किसान' चुनाव चिह्न है और कार्यकर्ताओं की तो कमी ही नहीं है। हमारे पास वह सब है जो चुनाव के लिए जरूरी है। अभी हम अराजनीतिक हैं, बस केवल 'अ' शब्द (उपसर्ग) ही तो हमें हटाना है।

माया : प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने आपकी शर्तों पर समझौते की पहल की। आप तिवारीजी को किस नजरिये से देखते हैं?

टिकैत : नारायण दत्त तिवारी ठीक आदमी है, लेकिन उसका संगसाथ बढ़िया नहीं है। हां, यदि उसकी चले, तो वह किसानों की समस्याएं हल करने से कतरायेगा नहीं।

माया : जवाहर रोजगार योजना के बारे में आपके विचार?

टिकैत : जिस गांव का नाश कराना हो, वहीं यह योजना कारगर होगी। गांव का प्रधान पैसे खायेगा और गांववासी उसका मुंह ताकेंगे। वास्तव में यह 'जवाहर योजना' नहीं, बल्कि गांवों के लिए 'जहर योजना' है।

—सुरेश द्विवेदी और राजेंद्र कुमार

संगीत के साथ
समय मिलाइये

MIRACLE EYE
SOUND AUTO CONTROL
12 MELODY HOUR STRIKE
Ajanta®

मिरैकल आई में समयबद्ध घड़ी है
और रात के अंधेरे में संगीत नहीं सुनाती।

वक्त बताए
घण्टों की याद दिलाए
पल-पल खुशहाल बनाए
नींद में भी खलल न लाए.
हर पंद्रह मिनट में— ¼ संगीत बजेगा
हर तीस मिनट में— ½ संगीत बजेगा
हर पैंतालीस मिनट में— ¾ संगीत बजेगा
हर साठ मिनट में— पूरा संगीत और घंटा बजेगा

म्यूज़िकल घड़ियों
के लिये भारतमें बेजोड़

Ajanta®
QUARTZ
कल की तकनीक का कमाल

रजिस्टर्डऑफिस :
पृथ्वीराज प्लॉट, पो.बॉ नं—११५
मोरवी-३६ ३६ ४१ (गुजरात)
फोन :३६२७, २२८०, २४५७, २४३३
टेलेक्स : ०१६८-२१२ ATCM
ग्राम : वनिथा

M207
M267
M227
M257

सभी बड़ी दुकानों में उपलब्ध
चेतावनी : कृपया हर मशीन पर अजंता की मोहर देखना न भूलें! नक़ल से सावधान रहें!

आधा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ पटवा का मोर्चा

आक्रामक अभियान. सुंदरलाल पटवा

ज्यों-ज्यों चुनाव निकट आ रहे हैं, त्यों-त्यों मप्र में चुनौतियों और लांछनों का दौर तेज होता जा रहा है। आरोपों-प्रत्यारोपों के इस युद्ध मे सत्ता और विपक्ष दोनों के मल्ल शरीक हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोलने में अग्रणी हैं, भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, स्वायत्त शासन राज्यमंत्री तनवंत सिंह कीर और गृहउपमंत्री विजय दुबे उर्फ काकू भाई ने। इस द्वंद्व में जनता दल भला पीछे क्यों रहें? जद नेता रामानंद सिंह ने इन दिनों सरकार को आड़े हाथों ले रखा है। वीपी सिंह की तर्ज पर रामानंद ने मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती तक दे रखी है।

पटवा बनाम काकू: पिछले दिनों राज्य विधानसभा के भीतर-बाहर सबसे तेज लड़ाई पटवा और काकू भाई के बीच देखने को मिली। काकू भाई विवादों के घेरे में तब आये, जब पटवा ने इटारसी स्थित 'नर्मदा मिनरल्स' फर्म को लेकर कई आरोप लगाये। उन्होंने काकू भाई पर अवैध जमीन की खरीदी और जंगल की कटाई के भी आरोप लगाये। पटवा ने उपमंत्री को अलवी बाबा नामक मीसा बंदी की सहायता करने के लिए भी आड़े हाथों लिया।

पटवा का निशाना: विजय दूबे

१७, एमजी रोड, इटारसी स्थित जिस नर्मदा मिनरल्स को लेकर पटवा ने काकू भाई को विवादों में फांसा, उसमें काकू भाई के भाइयों-संजय दुबे और अभय दुबे की पचास प्रतिशत भागीदारी है। पटवा के अनुसार, उपरोक्त कंपनी न केवल अवैध रूप से जमीन-खरीदी और जंगल-कटाई में, बल्कि खनिजों के अवैध उत्खनन में भी लिप्त रही। पटवा ने 'माया' से कहा, "इन आरोपों की जांच के लिए एक आईएएस अधिकारी, डीएफओ और डिप्टी कलेक्टर की समिति बनी थी। इस समिति ने जमीन की खरीदारी को निरस्त कर अवैध उत्खनन और वन-कटाई को रोकने की अनुशंसा की थी। मगर दुबे के दबाव के कारण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी।" इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में 'माया' ने जब काकू भाई से संपर्क साधा, तो उन्होंने न केवल इन आरोपों से इनकार किया, वरन पटवा पर नये आरोप जड़ दिये। पटवा को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, "पटवा आरोप सिद्ध कर दें, तो मैं न केवल त्यागपत्र दे दूंगा, बल्कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास भी ले लूंगा।" काकू भाई का कहना है कि उनके भाइयों की नर्मदा मिनरल्स में भागीदारी जरूर है, लेकिन अवैध खरीदी, अवैध कटाई और अवैध उत्खनन के आरोप सरासर गलत हैं। नर्मदा मिनरल्स को जमीन एक साल की लीज पर दी गयी थी, लिहाजा, एक साल बाद लीज रद्द हो गयी। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपने बचाव के साथ ही पटवा पर आरोप जड़ते हुए काकू भाई ने कहा कि पटवा दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाने में तो माहिर हैं, पर अपनी नाक के नीचे नहीं देख पाते, "पटवा के भतीजे की फर्म पटवा अभिकरण, इंदौर ने भूमि का अतिक्रमण कर रखा है। इसी प्रकार मंदसौर में पटवा की अवैध खदानें चल रही हैं, जिनसे विक्रम सीमेंट को चूना-पत्थर की आपूर्ति की जाती है।" होशंगाबाद के बहुचर्चित अलवी बाबा से अपने संबधों को नकारते हुए काकू भाई ने कहा कि पटवा ने अपने मित्र मोहम्मद शफी के इंदौर में निर्मित होटल के निर्माण में अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

जिस तरह काकू भाई, पटवा के आरोपों से इनकार करते हैं, उसी प्रकार पटवा, काकू भाई के आरोपों को निराधार बताते हैं। वे कहते हैं, अवैध उत्खनन का आरोप असत्य है। ये खदानें लीज पर मिली हैं और इनमें कोई भी अनियमितता नहीं बरती गयी है।" पटवा के अनुसार, उन्होंने खदानों की लीज के लिए अर्जी जनता सरकार के समय दी थी, जनता काल में वे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। वे चाहते, तो इन अर्जियों को दो दिन में निपटा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंततोगत्वा उन्हें इन खदानों की लीज सन ८३-८४ में कांग्रेस-इ शासन के दौरान मिली। पटवा इस बात से साफ इनकार करते हैं कि इंदौर स्थित पटवा अभिकरण ने अतिक्रमण किया है। वे कहते हैं, "दुर्भाग्यवश जो लोग अतिक्रमण की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं कि यह भूमि चौधरी परिवार से किराये पर ली गयी है और उसका तिमाही किराया २७ हजार रुपये है। काकू भाई को संभवत: यह ज्ञात नहीं है कि इस मामले की जांच अर्जुन सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में करायी थी।"

गुंडे को प्रश्रय: काकू भाई आरोपों से विंधे अकेले मंत्री नहीं हैं। स्वास्थ्यमंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी और स्वायत्तशासन राज्यमंत्री तनवंत सिंह कीर भी विवादों के घेरे में हैं। सिद्दीकी पर असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप है। इस सिलसिले में रायसेन जिले के मुख्तार नामक गुंडे का नाम लिया जाता है। मुख्तार के खिलाफ १७ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उस पर एक हरिजन महिला से बलात्कार करने का भी आरोप है। इस व्यक्ति के साथ रायसेन कलेक्ट्रेट में चर्चा करते हुए सिद्दीकी का फोटो भी उपलब्ध है। बताया जाता है कि यह फोटो तब खींचा गया था, जब मुख्तार हरिजन महिला से बलात्कार के मामले में फरारी काट रहा था।

पटवा कहते हैं कि मुख्तार की पीठ पर एक नहीं दोनों सिद्दीकियों के हाथ हैं। रसूल अहमद जहां उसे लेकर रायसेन के कलेक्टर से भेंट करते हैं, वहीं पूर्व राज्यमंत्री और भाजपा छोड़कर कांग्रेस-इ में आये नेता हसनात सिद्दीकी उसके साथ दावतें उड़ाते हैं। मुख्तार की तरह रजीउल्ला को भी सत्तारूढ़ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जब पीठ पर मंत्रियों और विधायकों के हाथ हों, तो पुलिस-प्रशासन कार्रवाई कैसे करे?

सुंदरलाल पटवा की आरोपों की बौछार झेलनेवाले मंत्रियों में अगला उल्लेखनीय नाम है, तनवंत सिंह कीर का। तनवंत कभी अपने भाई के होटल के कारण काफी चर्चित रहे थे, मगर इधर वे नये कारणों से सुर्खियों में आये। विधानसभा के पिछले सत्र में हंगामा तब हुआ, जब खबर उड़ी कि कीर और त्योंथर के कांग्रेस-इ विधायक गरुड़ मिश्र में हाथापाई हो गयी।

'माया' के सूत्रों के अनुसार मंत्री और विधायक में द्वंद्व का मुद्दा रींवा नगर निगम के एक अधिकारी का तबादला था। बताते हैं कि कीर के लगातार हीलेहवाले और टालमटोल पर विधायक के सब्र का प्याला छलक गया और उसकी कीर से तीखी नोकझोंक हो गयी। इस प्रकरण की पुष्टि और कथित कथा का खंडन-मंडन मुश्किल है, क्योंकि गरुड़ मिश्र ने आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है और वे कुरेदने पर भी कुछ कहते नहीं, मुस्कराते भर हैं। उधर कीर न केवल प्रकरण को मनगढ़ंत बताते हैं, वरन चुनौती के अंदाज में यह भी कहते हैं कि कीर को हाथ लगानेवाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। वे पटवा के इस आशय के आरोप से भी साफ-इनकार करते हैं कि उन्होंने लुधियाना में चार भूखंड खरीदे हैं। उन्होंने 'माया' से बातचीत में कहा, "पटवा बातबहादुर हैं। अगर वे अपना आरोप सिद्ध कर दें, तो मैं विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें (पटवा को) इस्तीफा दे देना चाहिए।" कीर आगे कहते हैं, "पटवा स्वयं को प्रांतीय स्तर का बड़ा नेता मानते हैं। अगर उनमें दम है, तो मेरे इलाके से आकर चुनाव लड़ें।"

कीर की लीक पर चलते हुए रसूल अहमद सिद्दीकी ने भी पटवा को चुनौती दे रखी है कि वे झूठी तोहमतें लगाने से बाज आयें। वे कहते हैं, "अपराधियों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। पटवा गंदे राजनीतिक खेल खेलने के आदी हैं।"

तनवंत सिंह कीर

कीर ने 'माया' से बातचीत में कहा, "पटवा बातबहादुर हैं। अगर वे अपना आरोप सिद्ध कर दें, तो मैं विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं।

पटवा ने गत दिनों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मंडीदीप-अध्यक्ष पद पर कमर मजीद नामक व्यक्ति की नियुक्ति पर भी उंगली उठायी है। वे इसे राजनेताओं और अपराधियों के बीच दिनोदिन प्रगाढ़ होते जा रहे रिश्तों की कड़ी मानते हैं। मजीद पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ दफा ११० के तहत कार्रवाई की अनुमति पुलिस ने शासन से मांगी थी।

झूठी सफाई : सुंदरलाल पटवा ने इन दिनों अकेले वोरा सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों से मोर्चा ले रखा है। बंबई के 'लाल बत्ती' प्रकरण का हवाला देकर वे जनशक्ति नियोजन राज्यमंत्री चंद्रकुमार भनोत को आये दिन कोंचते रहते हैं। उनके आरोपों के दायरे में गृहमंत्री कैप्टन जयपाल सिंह और पंचायत मंत्री शिवप्रताप सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की टीम के खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त उनके पास है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आ रहे हैं, पटवा अपने तरकश से तीर निकालते जा रहे हैं। दिक्कत यही है कि तेजतर्रार पटवा झोंक में बहुधा मर्यादा की सीमाएं लांघ जाते हैं। उनके तेवरों से लगता है कि उनके थैले में अभी और भी पुलिंदे हैं। दूसरी ओर मंत्री और कांग्रेसी नेता प्रतिवाद की रौ में कई बार गच्चा खा जाते हैं। इससे जनसामान्य में उनकी और कांग्रेस-इ की साख बिगड़ रही है जिसका प्रभाव अगले चुनाव पर भी पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर काकू भाई ने राज्य विधानसभा में अलवी बाबा से संबंधों और उसे संरक्षण देने से इनकार तो किया, किंतु करीब चार साल पहले 'माया' से बातचीत में उन्होंने अलवी बाबा से संबंधों की बात स्वीकार भी की थी। मोतीलाल वोरा के पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में जब अलवी बाबा को मीसा में बंदी बनाया गया था, तो मुख्यमंत्री के समक्ष अलवी बाबा को छोड़ने की पैरवी करने और कोई नहीं, काकू भाई ही गये थे।

मप्र की समकालीन राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर दिनोदिन तेज होता जा रहा है। बैठे ठाले आरोप लगाना और आंख मूंदकर बेहिचक उनसे इनकार करना राजनेताओं की आदत में शुमार होता जा रहा है। लिहाजा, फिलहाल तो यही लगता है कि आनेवाले दिनों में आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर और अधिक तीखा व तेज होगा।

—एसपी त्रिपाठी

तितलियों की रंग बिरंगी छटा
दीवारों पर कैद करें.

गुणवत्ता, रंग व सुन्दरता में सर्वोत्तम
साथ ही किफ़ायती भी

अंगूर ® एवं चेरी

• लाइम कलर्स • ड्राई डिस्टेम्पर • सीमेंट ऑक्साइड कलर्स

बच्छराज कलर्स (प्रा) लि.
रजि. कार्यालय : मच्छरहट्टा, पटना सिटी-८०००0८
दूरभाष : ४२३८९, ४२०९२, ४१११५
शाखा कार्यालय : १११ सेक्टर ३७, नोएडा-२०१३०१
दूरभाष : २२०५०

mahima/bcpl/89

छि:, कितना अश्लील है!
क्या?
वही...जो वहां पड़ा धूप खा रहा है...
ओह, मेरा ब्रान्डो! पूरे कमरे को
रोशन कर रहा है, है न?

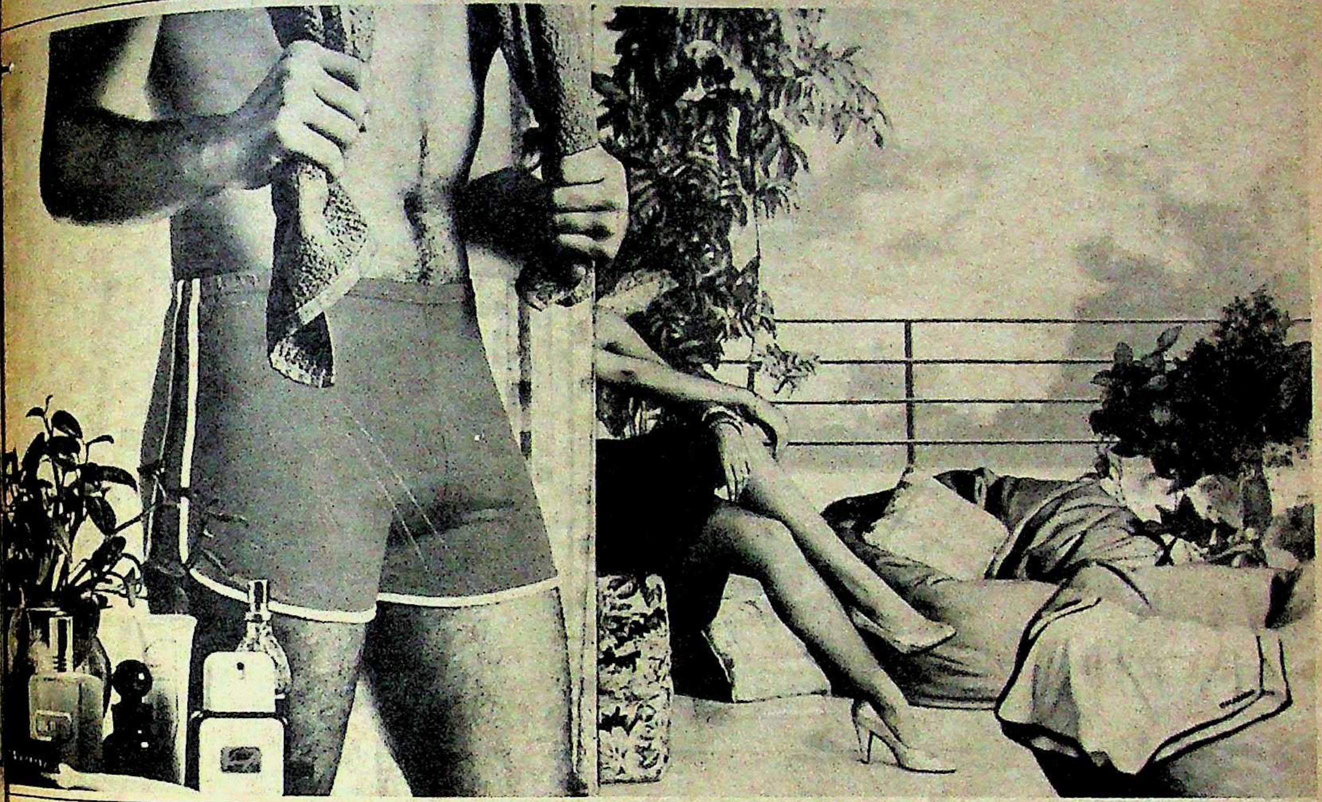

हुं...तुम्हारी अश्लील पसंद को रोशन
कर रहा है!
अरे,इसने पूरी दुनिया को दीवाना
बना दिया है!
हो सकता है...
और इसकी फिटिंग कितनी सही,
कितनी अच्छी है...
लेकिन मैं पूछती हूं,
इनके पास कोई सादे रंग नहीं हैं क्या?
हैं क्यों नहीं, सादे रंगों की तो पूरी
रेंज है.
पर वो हैं सीधे-सादे लोगों के
लिए.
हूं! और तुम्हारे लिए चटक पीला
और तोते जैसा हरा रंग, क्यों?
और जो रंग मैंने अभी पहना है
वो देखोगी तो दंग रह जाओगी.
गहरा गुलाबी होगा और क्या?
लो खुद ही देख लो...
अरे रे...ना बाबा ना...बचाओ...!

VIP
ब्रान्डो
नये अंदाज़ के अंडरवियर.

दिक्कत सिर्फ यह है, कि इसके चर्चे बहुत होते हैं।

Avenues HH:639

'पंछी'

परदेशियों का दर्द

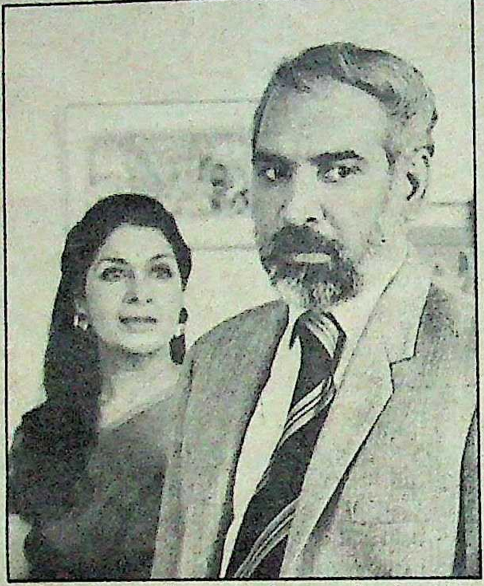

बनवारी तनेजा (भूपेंद्रबजाज) और सुषमा सेठ (सुमन)

मनोजकुमार की फिल्म 'पूरब और पश्चिम' में एक अत्यंत सामान्य, किंतु मर्मस्पर्शी दृश्य था जिसमें ३० वर्ष पूर्व विदेश में जा बसे सद्गृहस्थ मदनपुरी की बेटी नशे की आदी हो जाती है, बेटा हिप्पी बनकर जीवन नष्ट कर देता है और पत्नी को हाई सोसाइटी से फुर्सत ही नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में वह आहत मन अपने गमों को भुलाने के लिए किसी गोली या इंजेक्शन का सहारा नहीं लेता, बल्कि चुपके से जाकर एकांत कमरे में रेकार्ड बजाता है जिसकी धुन उसे एक रूहानी सुकून दिलाती है। उस फिल्म में गीत के बोल कुछ ऐसे थे—'बाबुल मोरा नैहर छूटो जाय...' एक तरफ बैकग्राउंड में यह गीत और परदे पर मदनपुरी के चेहरे पर बह रहे अविरल आंसू उद्वेलित कर देते हैं लोगों को, उन भावनाओं का सार समझने के लिए जिनमें विदेश में बसे, किंतु जमीन से जुड़े भारतीय जीते हैं।

इसी थीम के इर्द-गिर्द कहानी को बुनकर निर्माता सुदेश सयाल ने रवि बासवानी और करण राजदान के साथ मिलकर नया धारावाहिक 'पंछी' पेश किया है। कहानी का मुख्य तानाबाना बुना है लंदन में बसी तथा बीबीसी से जुड़ी मीरा सयाल ने। संवाद और पटकथा करण राजदान के हैं। निर्देशन रवि बासवानी का है जो इसके पूर्व 'किस्सा मियां बीवी' और 'हक्के-बक्के' जैसे पारिवारिक धारावाहिकों का निर्देशन कर चुके हैं। वैसे तो इसी कथ्य को लेकर दूसरे अंदाज में और भी सीरियल बन चुके हैं, लेकिन इस भावनात्मक ट्रीटमेंटवाले विषय को कोई भी सही रूप में कैमरे में कैद नहीं कर सका है। 'पंछी' एक ऐसे परिवार की कथा है जिसके बुजुर्ग भारत-स्थित अपने सगे-संबंधियों से बेहद प्यार करते हैं और उनसे मिलने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। लेकिन उन्हीं के बच्चों को उन संबंधियों से कोई खास लगाव नहीं रहता। वे भारत जाने के बाद नये परिवेश में काफी परेशान होते हैं। धीरे-धीरे अपने को बदल पाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब उन्हें भारत में अपनों से इतना प्यार मिलता है कि वे विदेश लौटने के लिए तैयार ही नहीं होते।

खेत में फूली सरसों की मनोहारी पीली छवि देखकर तथा मक्के की रोटी खाकर और वर्षा की पहली फुहार के बाद खेतों से उठनेवाली सोंधी-सोंधी महक लेकर जीनेवाला मनुष्य जब बुलंदियों को छूने के उद्देश्य से विदेश जाता है तथा शीर्ष पर पहुंच जाता है, तब उसे भौतिकता के खोखलेपन का अहसास होता है। वह पुन: कृत्रिमता से निकलकर कठिनाईभरी सचाई पा लेना चाहता है और अपनी वास्तविकता की ओर लौट जाना चाहता है।

अंतर्द्वंद्व: 'होली', 'दिवाली', 'वैशाखी' जैसे मौकों पर रिक्तता का अहसास करनेवाले सफल व्यापारी भूपेंद्र बजाज (बनवारी तनेजा) और उनकी पत्नी सुमन (सुषमा सेठ) अपने वतन की स्मृतियों को भुलाने में असमर्थ रहे हैं। वें पैसा, रुपया, शोहरत हासिल कर चुकने के बाद भारत लौट आना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे अनिता (बिनी परांजपे), अमित (विवेक लालवानी) तथा प्रिया (शिवाली पुरी) 'संपेरों' तथा 'जंगली जानवरों' के देश जाने की बात ही नहीं सुनना चाहते। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता की पोस्टिंग इंडिया में हो गयी है, तो इस खबर पर उनकी प्रतिक्रिया देखते ही बनती है। पंजाब की धरती पर स्वागत की परंपरा और संयुक्त परिवार की रिवायतों को देखकर इन बच्चों की घिग्घी बंध जाती है। वे इतने परेशान होते हैं कि उनको अपने ही रिश्तेदारों नातेदारों से चिढ़ हो जाती है। किसी तरह वे स्वागत-सत्कार के बाद जबरदस्ती खाना खाने के लिए बाध्य किये जाते हैं। सोने का कमरा किसी तरह शेयर तो कर लेते हैं; लेकिन रातभर मच्छर मारते हैं। उनका विदेश-प्रेम देखते ही बनता है। अनिता अपने आपको इतनी बच्ची नहीं मानती कि हर कोई उसका गाल मरोड़े। अमित को 'फास्ट लाइफ' खेतों-खलिहानों में नहीं मिलती, तो प्रिया अपने आपको सदैव अत्याधुनिक तथा भौतिक सुख-सुविधाओं के अभाव में पाती है।

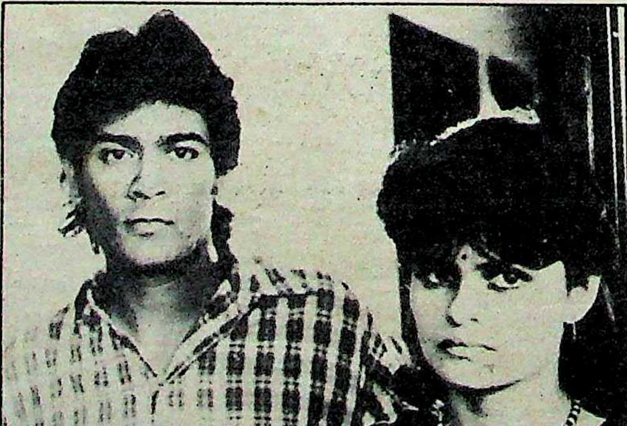

बिनी परांजये (अनिता) और विवेक लालवानी (अमित)

पहले दो एपीसोडों में बच्चों की दुविधा और मन:स्थिति तथा इसके बाद के एपीसोडों में सचाई तथा स्थिति से उनका सामना करते दिखाया गया है। अंत में ये बच्चे समझ पाते हैं कि जीवन भोगने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है।

सई परांजपे के प्रोडक्शन कंट्रोलर रह चुके सुदेश 'गांधी' व 'रेजर्स एज' के निर्माण से भी जुड़े रहे हैं। वैसे निर्माता के रूप में यह उनका पहला प्रयास है। कलाकारों में बनवारी तनेजा ने अपने पहले ही प्रयास में जबरदस्त छाप छोड़ी है। बच्चों को सुख से वंचित न करने तथा मातृभूमि आने के द्वंद्व को बनवारी ने बखूबी जीया है। कबीर सेठ हंसोड़ चाचा के रोल में ठीकठाक लगे हैं, लेकिन बिनी परांजपे कुछ खास नहीं कर सकी हैं।

—बंबई ब्यूरो

(सुषमा
तियों को
वें पैसा,
चुकने के
चाहते हैं,
ा (बिनी
(विवेक
(शिवाली
'जंगली
बात ही
उन्हें पता
ी पोस्टिंग
खबर पर
बनती है।
वागत की
रिवार की
बच्चों की
ने परेशान
रिश्तेदारों
है। किसी
के बाद
लिए बाध्य
मरा किसी
हैं; लेकिन
हैं। उनका
बनता है।
तनी बच्ची
उसका गाल
स्ट लाइफ
मिलती, तो
दैव अत्या-
-सुविधाओं

ों में बच्चों
स्थिति तथा
में सचाई
मना करते
में ये बच्चे
भोगने के
के लिए है।
प्रोडक्शन
'गांधी' व
भी जुड़े रहे
यह उनका
ाकारों में
से पहले ही
छोड़ी है।
न करने तथा
बनवारी ने
सेठ हंसोड़
ाक लगे हैं,
छ खास नहीं

-बंबई ब्यूरो

ALLWYN
QUARTZ
आल्विन क्वार्ट्ज़:
अपनेपन में आप जैसे
ALLWYN QUARTZ
Time FOR THE NEW GENERATION
ALLWYN
Manufactured under licence from
SEIKO
R K SWAMY/HAL/6958/HIN

आपका अपना अनोखा तरीका, अपनी ही खास मान्यताएँ होती है। समय के साथ साथ दौड़ रही इस दुनियाँ में, समय अपने साथ लिए हुए आप अलग खड़े है...

समय-प्रमाणित आल्विन क्वार्ट्ज़ संग्रहण। विश्व की सर्वोत्कृष्ट टैक्नोलॉजी के सहयोग से बनाई गई घड़ियाँ – उत्कृष्ट क्वार्ट्ज़ चलन, सुन्दर सोने या चमकीले स्टेनलेस स्टील केसिंग में। आपकी आँखों और कल्पनाशक्ति को चकाचौंध करनेवाले २५० से भी अधिक नमूनों में से चयन कर लीजिए। हर एक में अपनापन आप जैसे ही।

नेपाल

भारत से दुश्मनी मोल लेने का खमियाजा

नेपाल और भारत के घनिष्ठ पारंपरिक संबंध रहे हैं, लेकिन इन संबंधों में उस समय खट्टापन आ गया जब २३ मार्च, १९८९ को दोनों देशों के बीच पारगमन और व्यापार संधि समाप्त हो गयी। नेपाल ने ऐसे कौन से कदम उठाये, जिनसे भारत को चिंता हुई? भारत से संधि समाप्त होने के बाद क्या नेपाल की अर्थव्यवस्था की चूलें हिल गयी हैं? भारत की मदद के बिना नेपाल का जनजीवन किस घोर संकट में फंस गया है?

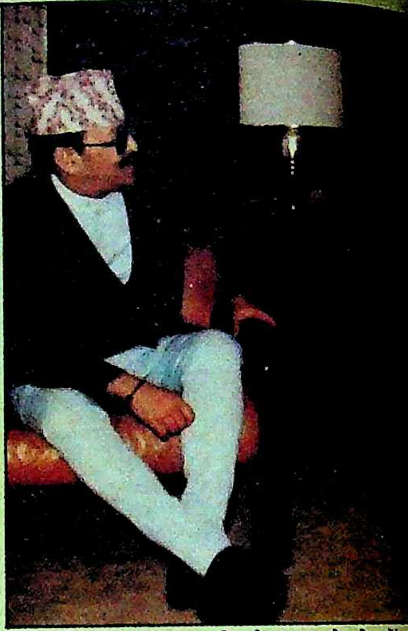

भारत से पुनः संबंध सुधारने की पहल : बेलग्रेड में

इस तथ्य से कौन वाकिफ नहीं कि टूटते संबंधों को जोड़नेवाले तो बिरले ही मिलते हैं, किंतु बिगाड़ की भनक पाकर प्रक्रिया को त्वरित कर रिश्तों में दरार डालनेवालों की कमी नहीं। फिर मामला यदि दो व्यक्तियों या परिवारों का न होकर दो राष्ट्रों तथा उनके मित्रवत संबंधों का हो, तब तो हर उस देश की बांछें खिल उठती हैं, जिसे अरसे से दो राष्ट्रों की दोस्ती खल रही होती है। कुछ ऐसा ही दरपेश आया भारत-नेपाल संबंधों की बिगाड़ के शुरू के दिनों में जब अपने को लगानेवाले नेपाल के पड़ोसी तथा दूरवर्ती देशों ने नेपाल की मदद की घोषणा की। अब तो स्थिति यह है कि काठमांडु को कोदारी से जोड़ने वाले ११४ किमी लंबे आरनिको मार्ग की मरम्मत तथा उसके पुनर्निर्माण के लिए स्विस डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने मास्टर-प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कुछ 'मित्र-राष्ट्रों', जिसमें चीन भी शामिल है, तथा वित्तीय संस्थाओं ने चीन द्वारा निर्मित आरनिको मार्ग के पुनर्निर्माण में सहायता करने का भी वचन दिया है। उल्लेखनीय है कि आरनिको हाईवे काठमांडु को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है जो फिलहाल साम्यवादी चीन के नियंत्रण में है। आरनिको हाईवे को ऐसे रास्ते में तब्दील किया जा रहा है जिस पर किसी भी मौसम में आवागमन बाधित न हो। सूत्रों के अनुसार पिछले साल इसी रास्ते से हथियारों से भरी हुई सैकड़ों ट्रकें चीन से नेपाल पहुंची थीं। चूंकि मार्ग काफी कमजोर था, इसलिए ट्रकों के आवागमन को सहन न कर सका तथा बुरी तरह टूट गया। ऐसे में चीन से नेपाल के बीच आवागमन का अवरुद्ध होना लाजिमी था। इसी दिक्कत से बचने के लिए इस मार्ग की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया। चीन के अलावा विश्व बैंक, स्विस डिवेलपमेंट कारपोरेशन तथा एशियन डिवेलपमेंट बैंक भी इस हाईवे के पुनर्निर्माण के काम में मदद करने को आगे आ गये हैं तथा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि इस संदर्भ को जेहन में रखते हुए मई '८६ में नेपाल के विदेश मंत्री शैलेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा दिये गये बयान का जायजा लिया जाये, तो भारत-नेपाल संबंधों में कहीं दरार के पीछे मौजूद कारण का पता लग जाता है। उपाध्याय ने कहा था कि यदि नेपाल में प्रवेश के दक्षिणी रास्ते बंद कर दिये जाते हैं, तो नेपाल उत्तर में प्रवेश मार्ग खोल लेगा। उपाध्याय के बयान से साफ जाहिर होता है कि भारत से संबंध बिगाड़ने में नेपाल खुद आगे-आगे था, क्योंकि उसे अपने पड़ोसी से भरपूर मदद तथा सहानुभूति की पूर्ण आशा थी। उल्लेखनीय है कि उपाध्याय के इसी बयान के साथ नेपाल के असरदार लोगों ने यह धारणा मजबूत करनी शुरू कर दी थी कि नेपाल के लिए दक्षिण के प्रवेश द्वार अब विशेष महत्व के नहीं रहे, क्योंकि नेपाल को

कृष्ण के अवतार के रूप में प्रचारित : नेपाल नरेश और सम्राज्ञी

प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नेपाल नरेश

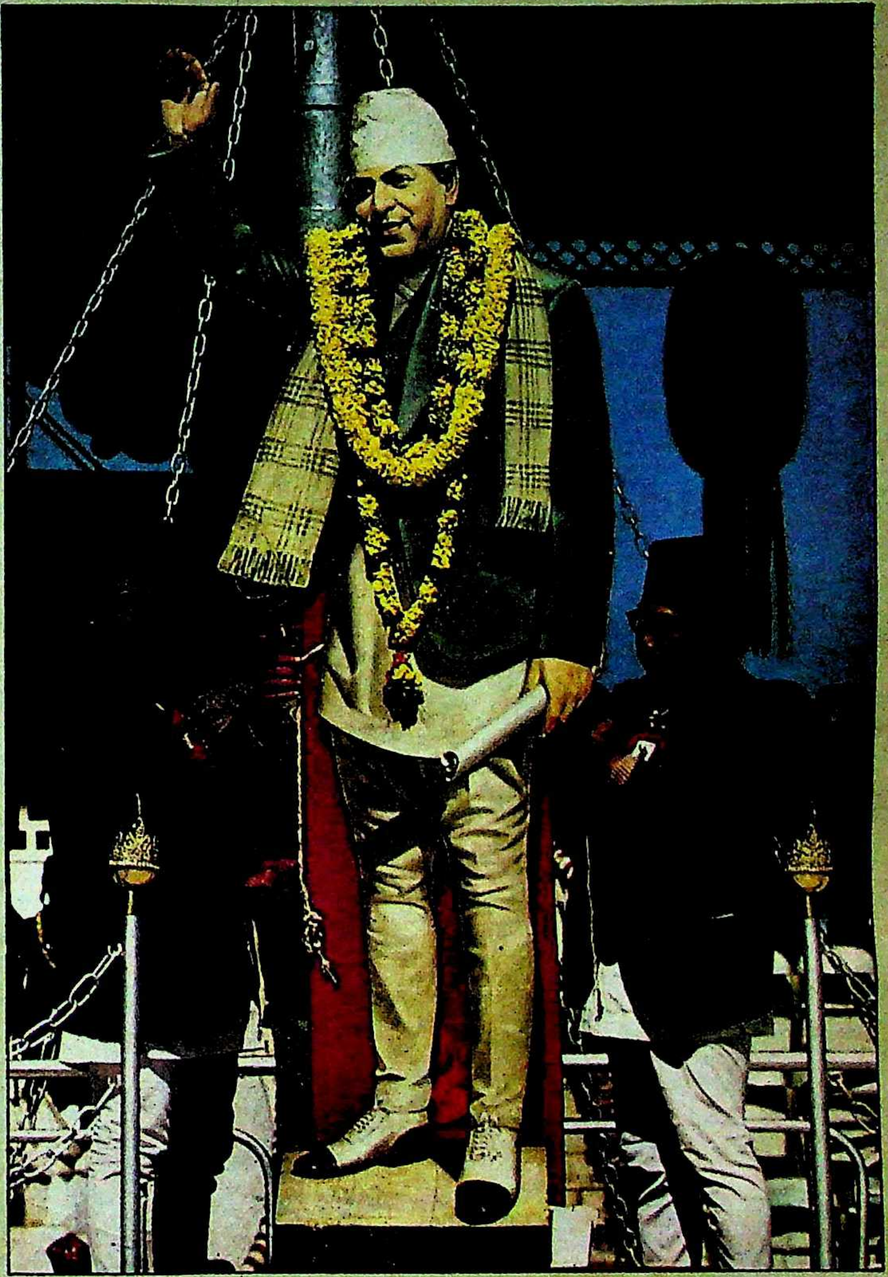

राजशाही के प्रति निष्ठा

चीनी शस्त्र: नेपाल के सुरक्षा गार्ड

रक्सौल के विकल्प के रूप में कोदारी मिल गया है। यही नहीं, चीन ने नेपाल को भरपूर मदद का जो आश्वासन दिया सो दिया ही, साथ में अन्य दूरवर्ती देश भी नेपाल के संकट के दिनों में अपनी सहानुभूति की बौछार करने से नहीं चूके। अमरीका, स्वीट्ज़रलैंड, जापान, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस तथा कुछ लगानेवाले खाड़ी देश भी अनुदान और सहायता के ऐलान के साथ आगे आये। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि वे चाहते हैं कि नेपाल अपने पैरों पर खड़ा हो जाये ताकि उसकी भारत पर निर्भरता समाप्त हो।

वक्ती सहानुभूति: ऐसे में यदि कोई यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर अचानक नेपाल के विकास के लिए इतने 'दोस्त' क्यों उत्सुक हो उठे तो अनुचित नहीं। फिर एक ऐसे देश की मदद के लिए लोगों का उत्सुक होना, जो ख़ुद विकास का पक्षधर नहीं दिखता, माहौल को संशयपूर्ण तो बनाता ही है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए अनावश्यक माथापच्ची करना बेकार है, क्योंकि अब यह बात राज नहीं रह गयी कि भारत से अपना दामन छुड़ाने के लिए नेपाल ने खुद अपने को अन्य राष्ट्रों के सम्मुख बतौर शतरंज पेशकर दिया था, ताकि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे आयें और नेपाल को भारत से छुटकारा मिल जाये। चूंकि नेपाल के भौगोलिक महत्व से विश्व के सभी देश परिचित हैं, इसलिए मौका गनीमत देखकर शक्तिशाली देशों ने नेपाल के संकट के दिनों में अपने मगरमच्छी आंसू बहाने से परहेज नहीं किया। यहां पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि नेपाल का वर्तमान संकट खुद नेपाल का पैदा किया हुआ है, किंतु अपने इस संकट का प्रचार नेपाल ने कुछ इस ढंग से किया कि अन्य देशों की

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ सें.मि. एफ़.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे का टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली ख़ूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?
ओनिडा २१
पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.
क्या नए ओनिडा पर प्रतिबंध लगाया जाए?

चीन का बढ़

यह लगे कि
बरता। फि
मसले ही भ
नहीं हैं। स
सालों से ऐ
को नागवार
से अपने ऐ
उद्देश्य से ह
हरकतों का
है, इतने
भौगोलिक
भी तो बुद्धि
हरकतों से
मई, १९
नरसिम्हार
१९५० की
नेपाल उल
एकपक्षीय

नेप
नेपाल की
है, किंतु ने
लिए इससे
जानता वि
तथा भार
बंगाल रा
को अपने
उसकी उ
महत्व है।
बदलने की
लाजिम थ
के नीति-
प्रतिपादि
के लिए
नेपाल मे

चीन का बढ़ता प्रभाव : नेपाल में चीनी सैन्य अधिकारी

यह लगे कि भारत ने नेपाल के साथ न्याय नहीं बरता। फिर केवल व्यापार तथा पारगमन के मसले ही भारत-नेपाल संबंधों में दरार के कारण नहीं हैं। सचाई तो यह है कि नेपाल पिछले कुछ सालों से ऐसी बेजा हरकतें कर रहा था जो भारत को नागवार महसूस हो रही थीं। यही नहीं, नेपाल से अपने ऐतिहासिक रिश्तों को बरकरार रखने के उद्देश्य से ही समय-समय पर भारत ने नेपाल की हरकतों का उसे अहसास भी दिलाया था। जाहिर है, इतने पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक संबंधों को पलक झपकते ही तोड़ देना भी तो बुद्धिमानी नहीं थी। किंतु जब नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तब मजबूर होकर ५ मई, १९८९ को भारत के विदेशमंत्री नरसिम्हाराव ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि १९५० की भारत-नेपाल संधि का समय-समय पर नेपाल उल्लंघन कर रहा था तथा उक्त संधि एकपक्षीय हो गयी थी।

नेपाल का महत्व : यह सच है कि भारत नेपाल की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता की कद्र करता है, किंतु नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन नहीं जानता कि नेपाल चीन अधिकृत तिब्बती क्षेत्र तथा भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच स्थित है। चूंकि भारत चीन को अपने लिए खतरा मानता आया है, इसलिए उसकी उत्तरी सुरक्षा व्यवस्था में नेपाल का अपना महत्व है। ऐसे में यदि नेपाल नजरें फेरे या पाला बदलने की कोशिश करे, तो भारत की नाराजगी लाजिम थी। वैसे भी पिछले कुछ सालों से नेपाल के नीति-निर्धारक कुछ इसी तरह की नीतियां प्रतिपादित कर रहे थे जो किसी रूप में भी भारत के लिए हितकर नहीं थीं। फिर भी चूंकि भारत नेपाल से अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए समय-समय पर नेपाली हरकतों की निशानदेही करके वह अपने संबंध मधुर बनाये हुए था। किंतु जब नेपाल ने चीन से हथियार आयात करने का फैसला किया, तो भारत को लगा कि पानी सिर से ऊपर चढ़ रहा है। यही नहीं, चीन से हथियार लेकर भारतीय सीमा पर तैनात किया जाना तथा नेपाली सेना की भारतीय सीमा के करीब अस्वाभाविक मुस्तैदी ने भी भारत को सोचने पर मजबूर किया। जाहिर है, नेपाल की दक्षिणी सीमा पर दूर तक मार करनेवाली बंदूकों से लैस सैनिकों की मुस्तैदी १९५० की संधि का उल्लंघन था। उल्लेखनीय है कि जब भारत को नेपाल-चीन हथियार सौदे की खबर मिली थी, तो उस वक्त भी नयी दिल्ली ने काठमांडु को अपनी नाराजगी का अहसास दिलाया था। किंतु काठमांडु सिर्फ यह कहकर खामोश हो गया था कि चूंकि सौदा हो चुका है, इसलिए उसे रद्द करने में नेपाल को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इस जवाब पर नयी दिल्ली ने काठमांडु को आगाह किया था कि यदि उसने सौदा रद्द नहीं किया, तो नेपाल को भविष्य में उसके बदले में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपायी आसान न होगी। किंतु काठमांडु के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। सच तो यह है कि नेपाल ने १९८७ की ग्रीष्म ऋतु से ही भारत से हथियार लेना बंद करके चीन से सौदे करने शुरू कर दिये थे। अचानक नेपाल द्वारा चीन से हथियार का आयात शुरू किया जाना जहां भारत के लिए चिंता का विषय था, वहीं नेपाल की शांतिप्रिय जनता भी हथियारों के आयात की खबरों से असमंजस में पड़ गयी थी। शुरू में जब चीन से हथियार आने की बात आम हुई, तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते थे। किंतु जब दो नेपाली साप्ताहिक समाचार-पत्रों 'योजना' तथा 'छानबीन' ने इस आशय के समाचार छापे, तो नेपाली जनता का भ्रम टूटना स्वाभाविक था। प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए चीन-समर्थक वामपंथी पत्रों ने जून '८७ में छापा था कि पिछले लगभग एक पखवारे से कोदारी-काठमांडु मार्ग सूर्यास्त के समय से आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है तथा इस बीच इस मार्ग पर उत्तर की ओर से ढंकी हुई सैनिक गाड़ियां गुजरती हैं। हालांकि किसी को यह पता नहीं था कि ढंकी हुई ट्रकों पर क्या लाया जाता है, किंतु एक धारणा-सी बन गयी थी कि ट्रकों पर नेपाली रायल सेना के इस्तेमाल के लिए हथियार लाये जा रहे थे। समाचार-पत्रों ने यह भी संदेह व्यक्त किया था कि हो न हो ट्रकों पर मध्य-दूरी वाली चीनी मिसाइलें भी लायी जा रही थीं। समाचार-पत्रों के अलावा नेपाल में स्मगलिंग का सामान बेचनेवाले दुकानदारों की बातों से भी इस बात की पुष्टि होती थी। इन दुकानदारों को शिकायत थी कि उनका व्यापार काफी घाटे में चल रहा है, क्योंकि लगभग एक पखवारे से शाम को काठमांडु-कोदारी मार्ग बंद हो जाता है। नतीजतन खासा से माल नहीं आ पाता था। इन खबरों से नेपाली जनता के असमंजस में पड़ने का कारण यह नहीं था कि चीन नेपाल को हथियार दे रहा था, बल्कि जनता को चिंता इस बात की थी कि आखिर नेपाल अपने किस दुश्मन से मुकाबला करने के लिए इतना हथियार एकत्र कर रहा है। जाहिर है, जब नेपाल की किसी से दुश्मनी नहीं तथा वह शांति का क्षेत्र घोषित किये जाने का इच्छुक रहा है, तो फिर उसे हथियारों की क्या जरूरत ?

हथियारों की आमद : नतीजतन सवाल उठ खड़ा हुआ कि कोदारी-काठमांडु के रास्ते से जो हथियार नेपाल पहुंच रहे थे यदि वे पड़ोसी के उपहार थे, तो भी क्या ऐसे उपहारों का भंडारण नेपाल के वश की बात थी ? चूंकि नेपाल को किसी

ओर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए यह माना जाने लगा कि काठमांडु हथियार सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर रहा था, ताकि नेपाल में लोकतंत्र की बढ़ती मांग को दबाया जा सके। किंतु फिर भी यह सवाल अनुत्तरित रहा कि चीन से ही हथियार लेने की नेपाल की क्या मजबूरी थी ? नेपाल में चीन से हथियारों के आयात पर प्रतिबंधित नेपाली कांग्रेस भी खामोश नही बैठी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टाराई ने 'माया' से कहा, "निस्संदेह हम भारी मात्रा में नेपाल में हथियारों के आयात से चिंतित हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि नेपाल किससे मुकाबला करने के लिए हथियार मंगा रहा है ?" ऐसे में भारत का चिंतित होना लाजिमी था, क्योंकि नेपाल भारत की उत्तरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

नतीजतन जुलाई '८८ के अपने दस दिवसीय विदेशी दौरे से भारत लौटकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्कालीन विदेशमंत्री नटवर सिंह को विशेष जहाज से विशेष दूत की हैसियत से नेपाल भेजा कि वे नेपाल नरेश बीरेंद्र से मिलकर नेपाल-चीन हथियार सौदे के प्रति भारत की नाराजगी जाहिर करें। बाद में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ तथा विदेशमंत्री नरसिम्हाराव ने भी अपने नेपाल दौरों के दौरान इस मुद्दे को उठाया। यही नहीं, नेपाल नरेश बीरेंद्र के सार्क के अध्यक्ष की हैसियत से भारत आगमन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इस मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। किंतु जब बीरेंद्र ने राजीव गांधी को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा कि यदि नेपाल भारत के प्रति अपना रवैया तब्दील नहीं करेगा, तो भारत मजबूर होकर अपना रवैया बदल देगा। इसी गरमागरमी के बाद २८ फरवरी, १९८९ को नेपाल में भारत के दूत ने नेपाल सरकार को एक पत्र लिखकर आगाह किया कि २३ मार्च, १९८९ को भारत-नेपाल व्यापार संधि समाप्त हो जायेगी। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों सरकारें एक नयी तथा संयुक्त व्यापार तथा पारगमन संधि हेतु विचार-विमर्श शुरू कर दें। यदि इस बीच संयुक्त संधि नहीं हो पाती और पूर्व संधि समाप्त हो जाती है, तो भी भारत विचार-विमर्श की स्थिति में कुछ दिनों तक व्यापार जारी रखेगा।

भारत की नाराजगी : भारत की ओर से संधियों की बाबत भेजी गयी आगाही नेपाल के कान खड़े करने के लिए काफी थी। इस आगाही के जवाब में नेपाल ने भारत से इस बात का आग्रह किया कि भारत अपने व्यापार तथा पारगमन की संधियों के प्रस्ताव पर पुनः विचार करे, क्योंकि दोनों संधियों को मिलाकर एक संयुक्त संधि की बात नेपाल के हित में नहीं। आग्रह के साथ-साथ नेपाल ने यह भी कहा कि भारत बदले की भावना से ग्रस्त होकर इस तरह से सोच रहा है तथा उसका संयुक्त संधि का प्रस्ताव सिर्फ नेपाल की भौगोलिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाना है। उल्लेखनीय है कि व्यापार तथा पारगमन की अलग-अलग संधियों की नेपाल की इच्छा जनता पार्टी की सरकार के समय बड़ी मुश्किल से पूरी हो पायी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मसले में हस्तक्षेप करके नेपाल के मनमाफिक दो अलग संधियों की बात मानी थी। ऐसे में पुनः संयुक्त संधि का प्रस्ताव नेपाल को पसंद कैसे हो सकता था ? इसी के साथ नेपाली सरकार ने भारतीय समाचार-पत्रों 'नवभारत, टाइम्स', 'इंडियन एक्सप्रेस' तथा 'जनसत्ता' और साप्ताहिक पत्रिका 'इलस्ट्रेटेड वीकली' पर नेपाल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का कारण यह बताया गया कि भारतीय मीडिया भारत-नेपाल संबंध बिगड़ने की गैरजरूरी बातें फैलाकर नेपाली जनता में संशय और निराशा पैदा कर रहा है, जबकि भारत-नेपाल संबंधों की वास्तविकता यह नहीं है। पाबंदी के संबंध में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी उसमें भारत के संयुक्त संधियों के प्रस्ताव के संबंध में यह कहा गया, "इस निर्णायक दौर में भी हम भारत से भावी व्यापार संबंधों पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। किंतु चूंकि संयुक्त संधि का प्रस्ताव पुनः स्थिति को ग्यारह वर्ष पीछे ढकेल देगा, इसलिए दोनों विषयों को अलग-अलग रखकर विचार किया जाना ही दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता का संकेत होगा। फिर चूंकि व्यापार दो देशों के बीच समयबद्ध संबंधों का विषय है तथा पारगमन दो देशों के बीच स्थायी जरूरत है, इसलिए दोनों विषयों को एक जगह रखना भी उचित नहीं।" उल्लेखनीय है कि जब व्यापार तथा पारगमन संधियों के समाप्त होने का समय करीब आया था, तो पुनः नयी संधियों के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेपाल नरेश से विचार-विमर्श का आग्रह किया था, किंतु नेपाली सरकार ने भारत के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया था। बल्कि राजीव गांधी के विचार-विमर्श के प्रस्ताव पर नेपाली प्रवक्ता ने सिर्फ यह कहकर बात आयी-गयी कर दिया था कि चूंकि नेपाल नरेश आखेट पर गये हुए हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच संधियों के संबंध में वार्ता संभव नहीं है।

इस तरह से संधियों की समापन तिथि आ गयी और नेपाल के ध्यान न देने के कारण २३ मार्च, १९८९ को संधियां समाप्त मानी गयीं। संधियों के समाप्त होने के संबंध में बयान जारी करते हुए भारतीय प्रवक्ता ने कहा था कि भारत का उद्देश्य नेपाली जनता को संकट में डालना नहीं है तथा संधियां समाप्त होने के बावजूद कुछ आवश्यक चीजें भारत नेपाल को पहुंचाता रहेगा जिसमें दवाएं तथा बच्चों का दूध शामिल है।

संकट के दिन : लेकिन संधियों के समाप्त होते ही नेपाल में जरूरत की चीजों को लेकर हाहाकार मचने लगा। २४ मार्च की सुबह नेपाली जनता को अपने संकटग्रस्त होने का अहसास होने लगा। मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल, चीनी तथा नमक आदि के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडु में उपभोक्ताओं की लाइनें लगने लगीं। हालांकि संधियां समाप्त होने के बाद भी भारत ने १५ प्रवेश द्वारों में से दो—जोगबनी तथर रक्सौल—

भारत द्वारा नेपाल को दिये गये अनुदान

इस तथ्य से कम लोग वाकिफ होंगे कि भारत से सबसे अधिक सहायता प्राप्त करनेवाला देश नेपाल ही है। १९५० से २३ मार्च, १९८९ तक भारत नेपाल को ३८० करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दे चुका है। १९८० में भारत ने नेपाल में पूर्वी-पश्चिमी राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस निर्माण का उद्देश्य नेपाल के दूरवर्ती क्षेत्रों को नेपाल के प्रमुख शहरों से जोड़ना है। इस योजना का बड़ा भाग पूरा हो चुका है। इस राज्यमार्ग का पूर्वी तथा मध्य भाग बन चुका है तथा पश्चिमी भाग का २०४ किमी लंबा मार्ग भी पूरा होने के करीब है। इस योजना पर कुल ५० करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। यही नहीं, भारत ने नेपाल की मोहाना नदी पर पुल बनाने के लिए भी अनुदान के रूप में दो करोड़ रुपए नेपाल को दिये।

हाल में भारत द्वारा पूर्वी नेपाल में राजबिराज नामक जगह पर १.८ करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक प्रांगण का निर्माण कार्य जारी था। इसके अलावा बिहार के रक्सौल क्षेत्र में एक पुल की योजना भी विचाराधीन थी। इस पुल से भारत तथा नेपाल को जोड़ने का लक्ष्य था। इस पर भी दो करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।

और-तो-और काठमांडु स्थित बीर चिकित्सालय जो इस वर्ष अपनी रजत जयंती मनानेवाला है, वह भी भारत की ही परियोजना का एक अंग है। इस चिकित्सालय पर भारत को ९.६ करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। बीर चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी भारत ने ही दिया है तथा वहां हर तरह की चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सालों से भारत द्वारा २५ से ३० करोड़ रुपए सालाना अनुदान के रूप में नेपाल को दिये जा रहे थे।

—कामाक्षी महिपाल

खोल रखे थे, किंतु नेपाली सरकार की चिंता यह थी कि मात्र दो रास्तों से आनेवाला थोड़ा-सा सामान नेपाल के लिए काफी न था तथा उसे नेपाल की पहाड़ियों में बसी आबादी तक पहुंचाना भी असंभव था।

बहरहाल, ११ अप्रैल को नेपाल ने भी आयातित सामानों पर लगनेवाले सीमा-शुल्क में फेरबदल किया। जहां काठमांडु ने कुछ सामानों पर शुल्क अत्यंत कम कर दिया, वहीं कुछ चीज़ों पर इतना बढ़ा दिया कि उन सामानों का नेपाल में महंगा होना लाजिमी हो गया, जो भारत से नेपाल पहुंच रहे थे। हालांकि काठमांडु ने अपने इस कदम की व्याख्या में यह कहा कि उसने ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठाया है, ताकि उसकी भारतीय निर्भरता समाप्त हो तथा नेपाली जनता का संकट समाप्त हो, किंतु भारत ने इस कदम को नेपाल की एक और शरारत माना, क्योंकि सीमा शुल्कों के संशोधन में सारा नजला भारतीय सामानों पर ही गिरा था। यही नहीं, नेपाल के व्यापारियों ने भी काठमांडु के इस कदम की भर्त्सना की तथा कहा कि काठमांडु का यह कदम नेपाल के लिए विनाशकारी होगा और आत्मनिर्भरता समाप्त होने के बजाय आर्थिक संकट विकराल होगा। साथ ही भारत-नेपाल के बीच स्मगलिंग भी बढ़ेगी।

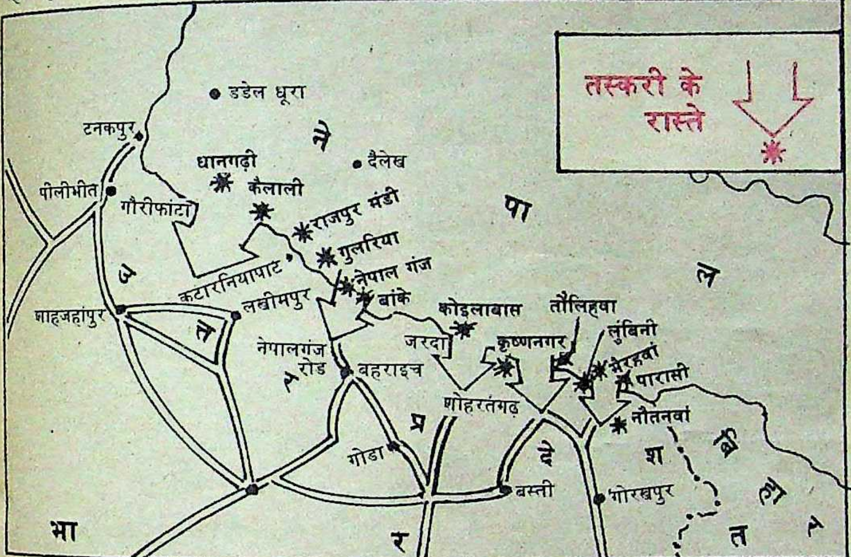

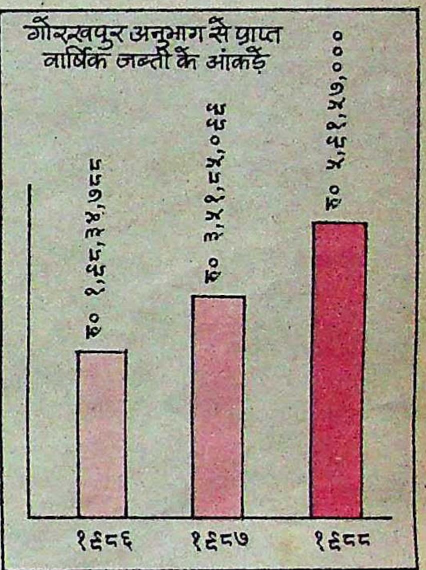

जानकारों का कहना है कि नेपाल में एक ऐसा अंतरंग गुट है जो तस्करी के धंधे का संचालन करता है। इस गुट में भारतीय व्यापारी भी हैं। ये लोग नेपाल में ऐसी वस्तुओं के आयात लाइसेंस प्राप्त करते हैं, जिन पर भारत में काफी नफा कमाया जा सकता है। ये लाइसेंस नफे में भागीदारी के आधार पर जारी किये जाते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में लौंग, बादाम और सिंथेटिक वस्त्रादि होते हैं। अधिकांश आयातित वस्तुएं कलकत्ता बंदरगाह से होती हुई जाती हैं। लेकिन होता यह है कि नेपाल जाने के बजाय ये जिस कलकत्ता से सीधे भारतीय काले बाजार में पहुंच जाती हैं। इसमें भारतीय सीमा शुल्क विभाग के लोगों की भी मिलीभगत होती है। एक अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष ५ हजार टन सिंथेटिक वस्त्रों का आयात हुआ था, जबकि नेपाल में मुश्किल से १०० टन की भी खपत नहीं थी। जाहिर है उसका अधिकांश भारत में बेचा गया। इस वर्ष लगभग १० हजार टन सिंथेटिक वस्त्रों का आयात करने के लाइसेंस प्राप्त किये गये हैं। नेपाल में लगभग २० ऐसे बाजार हैं, जहां सुई से लेकर बड़ी-से-बड़ी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इन बाजारों का कुल मिलाकर लगभग तीन हजार करोड़ टर्न ओवर है। ये केंद्र भारत-नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं।

हालांकि काठमांडु इस बात से वाकिफ था कि भारत से संबंध विच्छेद करने पर नेपाल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु अपनी संप्रभुता तथा स्वतंत्रता के घमंड तथा अपने अन्य दोस्तों के बलबूते वह भारत को अलविदा कह बैठा। संधियों के समापन के एक महीने बाद ही नेपाल में जरूरत के सामानों की आपूर्ति को लेकर त्राहि-त्राहि मचने लगी। नेपाल सरकार का यह भ्रम टूट गया कि नेपाल भारत के बिना भी जिंदा रह सकता है। भारत-नेपाल संबंधों के बिगड़ते ही नेपाल के आम आदमी की स्थिति चिंताजनक हो गयी। उसके लिए दो जून की रोटी कमाना दूभर हो गया।

बद से बदतर स्थिति: चूंकि नेपाल में ज्यादातर जरूरी सेवाएं भारतीयों के ही हाथ में थीं, इसलिए संधियां समाप्त होते ही संकट की भनक पाकर भारतीय वापस होने लगे। स्थिति यह हो गयी कि नेपाल के दमक नामक स्थान पर एक व्यक्ति ने 'माया' से बताया, "हमारे इलाके में तो बाल काटनेवाले ढूंढ़ने से नहीं मिल रहे हैं। सबके सब अपने वतन वापस चले गये।" असल में नेपाल सरकार की हजार कोशिशों के बावजूद नेपाल के लोगों ने बाल काटने की कला नहीं सीखी थी तथा जनता भारतीय बारबरों पर ही निर्भर करती थी। आमतौर से बेठिया, देवरिया, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के नाई ही नेपाल में हेयरकटिंग सैलून चला रहे थे। यही नहीं, नेपाली जनता को उनके दरवाजे पर अच्छी सब्जियां तथा फल मिलने भी बंद हो गये, क्योंकि भारत की सीमा से लगे गांवों के जो फेरीवाले नेपाल में सब्जियों की फेरी करते थे, उन्होंने भी नेपाल जाना बंद कर दिया। नतीजतन नेपालियों को नेपाल की पारंपरिक सब्जियों का इस्तेमाल शुरू करना पड़ा। इस बीच नेपाली सरकार जनता को सिर्फ यह आश्वासन देती रही कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

सरकार के आश्वासनों के बावजूद काठमांडु के व्यापारिक खेमों में चिंता और निराशा बढ़ती जा रही है। स्थिति यह हो गयी कि मंहगाई देखते-देखते २५ प्रतिशत बढ़ गयी और सरकारी राजस्व में कमी दिखायी पड़ने लगी। यही नहीं, नेपाल की आय के सभी स्रोतों में घाटा शुरू हो गया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमराने की स्थिति में पहुंच गयी। पर्यटन, परिवहन, दुग्ध व्यवसाय, कृषि, वन परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में घाटा शुरू हो गया। संधियां समाप्त होने के दो माह के बाद ही कृषि मंत्रालय ने ३६ करोड़ रुपए के घाटे का ऐलान किया। यही नहीं, किसानों को भी ६.५ करोड़ रुपयों का घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि परिवहन उपलब्ध न होने के कारण उनका माल बाजार तक पहुंच न सका। परिवहन के अभाव में १४,००० लीटर दूध की व्यवस्था भी नेपाल में बंद हो गयी। मत्स्य उद्योग में भी दो महीने के अंदर १.८ करोड़ रुपए का घाटा दर्ज

किया गया। इसके अलावा, वन मंत्रालय को इस बात की चिंता होने लगी कि ईंधन की जरूरत पूरी करने के लिए २४० हेक्टेयर क्षेत्र के पेड़ प्रतिदिन गिराये जा रहे थे। मंत्रालय के सूत्रों ने 'माया' को बताया कि प्रथम दो माह में ही ११३.३ करोड़ रुपए कीमत के पेड़ ईंधन के रूप में नष्ट किये जा चुके हैं।

उद्योग ठप हुआ : इसके अलावा नेपाल की ६० औद्योगिक इकाइयों में से २० तो दो महीने के अंदर ही पूरी तरह से ठप हो गयी तथा १.१ करोड़ रुपए का राष्ट्रीय नुकसान हुआ। उद्योग मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 'माया' को बताया कि उक्त २० इकाइयों में कार्यरत ७, १२६ मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां तो सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के अभाव में ही बंद हुई। जो फिलहाल किसी तरह चल रही हैं उनकी भी स्थिति नाजुक है। औद्योगिक उत्पादन में ५० प्रतिशत की कमी आयी है। होटल-व्यवसाय में भी बड़े नुकसान के संकेत मिले हैं, क्योंकि अप्रैल '८६ में ही होटलों में रहने वालों की संख्या में १८ प्रतिशत कमी आयी थी। ७५ प्रतिशत से ज्यादा वाहन सड़कों से आज भी गायब हैं जिनमें तीन पहियावाली गाड़ियां तथा टैक्सियां भी शामिल हैं। अप्रैल '८६ की स्थिति का जायजा लेते हुए सरकार ने गणना की थी कि वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर जून '८६ तक राष्ट्र को ३०० करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि सूत्रों का कहना है कि अब तक नुकसान कई गुना ज्यादा हो चुका है। हालांकि जून '८६ के बाद से सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की कुछ नियमित व्यवस्था की है, किंतु उससे मसले का हल होने वाला नहीं। स्थिति यह है कि काठमांडु की चमक-दमक वाली सड़कें वीरान सी पड़ी हैं। हालांकि सरकार ने अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए शुरू के दौर में परिवहन-व्यवस्था के अभाव में फैली गंदगी को बड़ी हद तक साफ करा दिया है। सड़कों पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर पुनः वाहन दौड़ते नजर आने लगे हैं, किंतु अचानक दोस्त बन गये देशों की अस्थायी मदद कितने दिनों तक नेपाली जनजीवन को राहत की सांस लेने का मौका देगी यह कहा नहीं जा सकता।

भारतीय विपक्ष का रवैया : यहां पर इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि नेपाली सरकार को इस बात का पूरा यकीन था कि यदि उसकी आनाकानी से नाराज होकर राजीव सरकार नेपाल से संबंध बिगाड़ने की बात सोचेगी भी, तो भारतीय विपक्ष तथा भारत के प्रबुद्ध नागरिक ऐसा होने न देंगे। शायद इसी भरोसे नेपाल भारत के संकेतों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था तथा विचार-विमर्श को टालता जा रहा था। किंतु जब भारत-नेपाल संबंधों के विषय पर राजीव सरकार के नजरिये से मेल खाता हुआ नजरिया भारतीय विपक्ष का भी सामने आया, तो नेपाल सरकार को पैर के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। इस संबंध में जनता दल के नेता चंद्रशेखर का बयान कि नेपाल अन्यत्र देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, नेपाल के लिए काफी घातक रहा। यही नहीं, भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कह डाला कि इतिहास से तो लड़ा जा सकता है, किंतु भूगोल से सामना करना मूर्खता है। वाजपेयी के इस बयान ने भी काठमांडु को सोचने पर मजबूर कर दिया।

जहां तक भारत-नेपाल संबंधों की बात है, नेपाल के बारे में भारत का नजरिया हमेशा यही रहा है कि नेपाल उसका पड़ोसी ही नहीं, वरन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे करीबी भी है। इस नाते भारत से विशेष सहायता का अधिकारी है। लेकिन हाल में नेपाल ने जिस तरह आनाकानी करके रिश्ते बिगाड़े उससे यह साफ जाहिर हो गया कि नेपाल स्वयं भारत की कृपा पर आश्रित नहीं रहना चाहता। वैसे भी यदि पिछले लगभग ३० साल के इतिहास को पलटा जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि शुरू से ही नेपाल का भारत के साथ रवैया 'खाये भी, गुर्रायें भी' वाला रहा है। उल्लेखनीय है कि २१

पर्यटकों की प्रतीक्षा

नेपाली मीडिया का जहर

लंबे अरसे तक नेपाली मीडिया की मुख्य जिम्मेदारी सीधे या घुमा फिराकर भारत के खिलाफ नफरत का अभियान चलाना रहा है। पिछले ३० वर्षों के दौरान शायद ही कोई ऐसा मौका निकला हो जब उसने भारत के नाम पर जहर नहीं उगला। हाल के चार-पांच महीनों में तो यह प्रायः प्रत्येक नेपाली पत्र-पत्रिका—चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी—का केंद्रीय विषय बन गया है। अफगानिस्तान, सिक्किम, मालदीव और श्रीलंका की घटनाओं तक की बड़ी बारीकी से आड़ लेकर, भारत को 'एक साम्राज्यवादी शक्ति' के रूप में देखने-दिखाने की नेपाल में जो प्रवृत्ति चला दी गयी है, वह न केवल आज भी चल रही है, बल्कि तब से चरम सीमा तक पहुंच गयी है, जब से सरकार के प्रवक्ताओं ने भारत को ऐसा देश करार देना शुरू किया है जो 'दास जनता', 'दास मानसिकता', 'दास संस्कृति,' 'दास साहित्य', 'दास इतिहास' वाला मुल्क माना जाता है। वे प्रवक्ता यह सवाल भी उठाने लगे हैं कि ऐसा देश (भारत) अपनी तुलना उस नेपाल से कैसे कर सकता है, जिसने कभी यह जाना ही नहीं कि दासता का अर्थ क्या होता है? एक पूर्व विमान चालक (राजीव गांधी) एक पूर्व अध्यापक (मारीचमान सिंह श्रेष्ठ) की बराबरी कैसे कर सकता है?

इस बात पर बहस फिजूल ही है कि किसके इशारे पर, रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के अतिरिक्त, छोटी-बड़ी करीब चार सौ नेपाली पत्र-पत्रिकाएं रात-दिन भारत विरोधी अभियान चलाये जा रही हैं। नेपाल के अधिकारी कहते हैं कि ये पत्र-पत्रिकाएं स्थानीय पाठकों के लिए छपती हैं और इनका उपयोग

जुलाई, १९५० को भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि हुई थी। इस संधि के तहत १९५१ में भारत ने महाराजा त्रिभुवन के विरुद्ध राणाओं के विद्रोह में महाराजा की सहायता की थी। नतीजतन जब महाराजा त्रिभुवन वापस काठमांडू पहुंचे, तो उन्होंने भारत से नेपाल के संबंध और मित्रवत बनाने का प्रयास किया। पचास के दशक का पूर्वार्द्ध दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग और मैत्री का रहा। दशक के मध्य में महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम की मृत्यु हो गयी। इसके बाद जब महाराजा महेंद्र गद्दी पर बैठे तब भारत और नेपाल के बीच दूरी बढ़ने लगी। इसके लिए भारत भी दोषी था। नेपाल ने राजमहल के लिए मोटरों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा मांगी थी। उल्लेखनीय है कि उस दौरान भारत को विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करना पड रहा था। किंतु नेपाल ने इसे भारत की मजबूरी नहीं माना तथा इसी बात को लेकर भारत से नाराज हो गया और दोनों देशों के बीच दरार पड़नी शुरू हो गयी।

चुटकी काटने की आदत : इतिहास साक्षी है कि यद्यपि भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन की संधि सितंबर १९६० में हो चुकी थी, उसके बावजूद नेपाल ने समय-समय पर भारत को चुटकी काटने में परहेज नहीं किया। १९६१ के आरंभ से ही नेपाल इस संधि की धाराओं पर आपत्ति करने लगा था। यही नहीं, नेपाल की जनप्रतिनिधि सरकार के समय से अधर में पड़ी कोदारी के रास्ते काठमांडू से ल्हासा तक सैनिक महत्व की सड़क बनाने की चीन की पेशकश को भी महाराजा महेंद्र ने स्वीकृति दे दी थी। इस पर भारत का नाराज होना स्वाभाविक था। महाराजा महेंद्र ने तो जो किया सो किया ही, उनके उत्तराधिकारी नेपाल नरेश बीरेंद्र के समय में इसी रास्ते से ट्रकों में भरकर चीनी हथियारों का नेपाल पहुंचना भला भारत को कैसे सहन हो सकता था? यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान संबंधों की असामान्य स्थिति बने रहने के कारण भी नेपाल के हौसले बढ़े थे और व्यापार तथा पारगमन के विभिन्न मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहने के साथ ही काठमांडू ने परोक्ष रूप से इस बात का भी संकेत दिया कि वह २१ जुलाई, १९५० की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि को बदलना चाहता है। अपने संकेतों को स्पष्ट करने के लिए उसने नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने की योजना को भी हवा देना शुरू कर दिया था। काठमांडू रेडियो से प्रायः यह प्रसारित किया जाता था कि भारत इस योजना का विरोधी है और चीन, ब्रिटेन, अमरीका तथा पाकिस्तान आदि देश नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित किये जाने के पक्ष में हैं।

यहां पर इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि १९५० की संधि की धारा १० के अनुसार दोनों देशों को संधि रद्द करने से पूर्व संधि पर विचार-विमर्श करना चाहिए था तथा संधि रद्द किये जाने के लिए एक वर्ष पूर्व अधिसूचना जारी करना लाजिमी था। किंतु दोनों में से किसी देश ने भी इस संधि के रद्द किये जाने से पूर्व अधिसूचना नहीं जारी की। हां, इतना जरूर है कि भारत की ओर से विचार-विमर्श का कई बार आग्रह जरूर किया गया।

बहरहाल, संबंधों में पिछले पांच महीनों में पड़ी वास्तविक दरार से नेपाल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित तो जरूर हुई है, किंतु अभी तक नेपाल ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है जिसे मद्देनजर रखकर यह कहा जा सके कि नेपाल को अपनी गलती का अहसास है। अलबत्ता काठमांडू ने ये संकेत जरूर दिये हैं कि वह अन्य देशों की तरह भारत से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने का पक्षधर है, किंतु किसी विशेष संबंध के लिए वह उतावला नहीं। पर्यवेक्षकों का मत है कि नेपाल भारत से विशेष संबंध सिर्फ इसलिए नहीं बनाये रखना चाहता, क्योंकि नेपाल में निर्दलीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद से नेपाल सरकार को हर समय राजनीतिक विद्रोह का खतरा सताता

किरोसिन तेल का अभाव: नेपाल का एक गांव

'रक्षात्मक' दृष्टि से किया जाता है। लेकिन नेपाली मीडिया भारत के प्रति कितना आक्रामक हो गया है, यह किससे छिपा है?

यह तो साफ है कि नेपाली मीडिया बेहद भद्दी जुबान इस्तेमाल में ला रहा है, वह भी ऐसे देश के प्रति जिसके साथ नेपाल के सबसे नजदीकी और अटूट संबंध थे। लेकिन क्या इसके लिए मीडिया को ही कोसना उचित होगा? क्या इसके लिए वह बाध्य नहीं है? जिस देश में प्रधानमंत्री और ख्यातिप्राप्त विद्वानों से लेकर ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं तक प्रत्येक व्यक्ति सरकार के इशारे पर नाचने के लिए विवश और आदी हो गया हो, वहां की पत्र-पत्रिकाओं और रेडियो-टेलीविजन से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? यह चाहे प्रणाली (शासन) की देन हो या करिश्मा, नेपाल के लोग ऐसा रुख अपनाने को मजबूर कर दिये गये हैं। ऐसे में इस भारत विरोधी लहर के लिए मीडिया को दोषी ठहराने का मतलब 'खेत खाये गधा, मारा जाये जुलाहा' जैसा ही होगा।

भारत और नेपाल के लोगों के बीच स्थायी शत्रुता पैदा करने के लिए कितना गहरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसका अंदाज लगाना हो, तो एक दिन सुबह-सुबह रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन खोलकर बैठ जाइए और शाम तक चलनेवाले कार्यक्रमों का जायजा लीजिए। फिर आपको कोई दुविधा नहीं रह जायेगी। नेपाल टेलीविजन से प्रसारित होनेवाला एक कार्यक्रम है 'तड़हा को बस्ती', यानी दूर का गांव। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक गांव के एक बर्बर और क्रूर जमींदार की कहानी दिखायी जाती है, जो गांव के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्ग को लूटने-खसोटने के अलावा महिलाओं से बलात्कार और उन पर अत्याचार भी करता रहता है। यह कहानी इस टिप्पणी के साथ खतम होती है कि भारत इस जमींदार जैसा ही हो गया है। इसी तरह कश्मीर को 'भारत-अधिकृत कश्मीर' कहना और उसे पाकिस्तान का हिस्सा बताना, रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन का रवैया बन गया है।

घर भर के धूल-मैल से मुक्ति की सबसे सुविधाजनक युक्ति समझाने, दिखाने आया है यूरेका फोर्ब्स से आपका ये दोस्त.

अगले कुछ दिनों के बीच यूरेका फोर्ब्स का सेल्समेन आपके दरवाजे पर आएगा और अपना परिचय-पत्र दिखाएगा.

वह आत्मविश्वास जगाएगा – और क्यों न जगाए... उसका संबंध भारत में अपनी तरह के सबसे बड़े व सफल बिक्री-संगठन से जो है, साथ ही जो, बिक्री-बाद विश्वसनीय सेवा भी देते हैं.

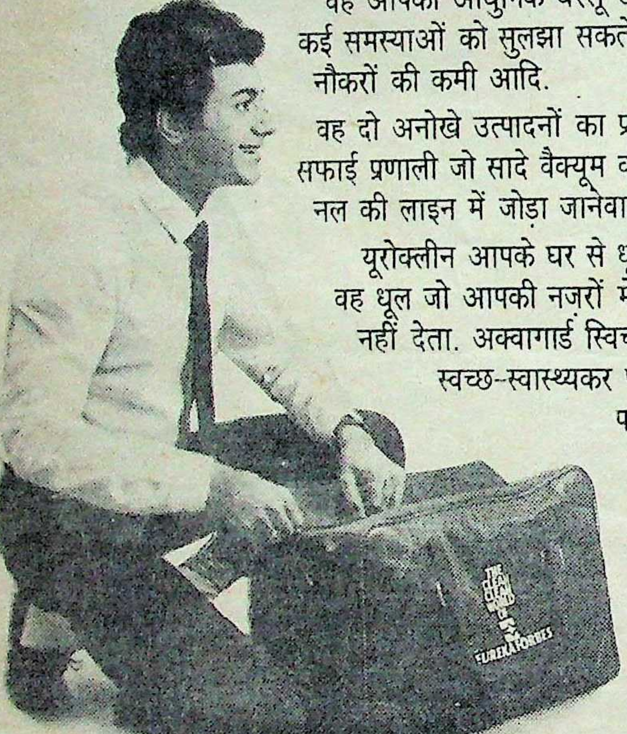

वह आपको आधुनिक घरेलू उत्पादनों की जानकारी देगा, जो आजकल की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जैसे कि धूल, प्रदूषित पेयजल, प्रदूषण, नौकरों की कमी आदि.

वह दो अनोखे उत्पादनों का प्रदर्शन करेगाः यूरोक्लीन – एक बहु-उपयोगी सफाई प्रणाली जो सादे वैक्यूम क्लीनर से कहीं आगे है, और अक्वागार्ड – नल की लाइन में जोड़ा जानेवाला वाटर फिल्टर-कम-प्यूरिफायर.

यूरोक्लीन आपके घर से धूल और कचरा चुन-चुन के निकालता है – वह धूल जो आपकी नज़रों में कभी न आई हो. फिर भी जरा सी परेशानी नहीं देता. अक्वागार्ड स्विच खोलने के बाद नल चालू करते ही स्वच्छ-स्वास्थ्यकर पीने का पानी देता है, चाहे नल के पानी में पहले कितने ही जीवाणु (बैक्टीरिया) हों.

यूरेका फोर्ब्स का सेल्समेन आपको घर पर ही आकर बताएगा कि किस तरह इन उत्पादनों द्वारा आप अपने घर को स्वच्छ व स्वास्थ्यकर बना सकते हैं, और ये आधुनिक उपाय आपके परिवार के लिए कितने लाभकारी हैं.

हमारा सेल्समेन आपके घर आएगा यही सोच कर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. उसे बुलाने के लिए नीचे दिये किसी भी पते पर यूरेका फोर्ब्स से आप संपर्क कर सकते हैं. या फिर इस पते पर लिखिए – यूरेका फोर्ब्स, पो.ऑ. बॉक्स 936, जी.पी.ओ. बम्बई 400 001.

यूरोक्लीन के बिक्री व सेवा केन्द्र इन स्थानों पर हैं, तारांकित स्थानों पर अक्वागार्ड भी उपलब्ध है.

यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, मुख्यालय : फोर्ब्स बिल्डिंग 4थी मंजिल, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, बम्बई- 400 001
फोन : 2047870 (5 लाइन्स) **बम्बई :** *1. अल हामाल 50, पाली रोड, बान्द्रा फोन : 6442741/42. *2. "आशादीप"
... 23, आजाद रोड, अंधेरी (पूर्व), फोन : 6323771 *3. डी-16, कॉमर्स सेन्टर, ताड़देव मेन रोड
फोन : 4949183/6184 *4. बी-3, ... होम अपार्टमेंट्स, 1ली मंजिल, 56, वुडहाऊस रोड, कोलाबा
फोन : 217458/217430. *5. 71, ... 2री मंजिल, ... फैक्ट्री के सामने, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुण्ड (पश्चिम)
फोन : 5601082/5619148 ● **कलकत्ता :** *6. 7, चक्रबेरिया रोड (दक्षिण) फोन : 477954/5402 *7. "प्रिया" बी डी-9
1ली मंजिल, सेक्टर I, साल्ट लेक सिटी, फोन : 347799. *8. 177, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, देशबन्धु पार्क के सामने, श्याम बाजार
फोन : 555624. 9. 1ली मंजिल, 19, एन.एस. रोड, पुलिस स्टेशन व जिला हावड़ा, फोन : 674255 ● **दिल्ली :** *10. 402,
अर्चना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, फोन : 6416143/6463606 *11. 12/4, आसफ अली रोड, मित्तल
बिल्डिंग फोन : 278055/270523/266890/2667302 *12. एम/37, ग्रेटर कैलाश-2 मार्केट,
फोन : 6449727/6433827/6463041. *13. 203-204, जमुना हाऊस, 2री मंजिल, म्युनिसिपल नं 10203,
... करोल बाग फोन : 5717722/5442/5736268. *14. 17ए/41, W.E.A., जसाराम हॉस्पिटल के सामने
मद्रास : *15. 733, अन्ना सलाई, 2री मंजिल, फोन : 869846/861413. *16. ईस्ट कोस्ट चेम्बर्स, 2री मंजिल
... टी.एम. सेंट्री रोड, टी. नगर, फोन : 446610/17. *17. 75, 1 एवेन्यु, इंदिरा नगर, आडयार ● **अहमदाबाद :** *18.
... सोसाइटी, गुजरात विद्यापीठ के सामने, आश्रम रोड, फोन : 446982/466821/465320 ● **इलाहाबाद :** 19.
युनाइटेड टॉवर, 53, लीडर रोड ● **अमृतसर :** 20. 484, ग्रीन एवेन्यु, फोन : 62111 ● **बंगलौर** *21. फराह कमर्शियल
कॉम्प्लेक्स, 68, जे.सी. रोड, फोन : 224453/225673. *22. 4305, हाई पॉइन्ट- 4, 3री मंजिल, 45, पैलेस रोड
फोन : 27746 ● **बरोडा :** *23. दीप ज्योति, 75, सुवर्ण पुरी सोसाइटी, चीकूवाडी. फोन : 322681/322289 ● **भुवनेश्वर**
24. 16/8, भुवनेश्वर होटल के पीछे, (कटक रोड). फोन : 57018 ● **कालीकट :** 25. "अयोध्या", 1/3698, ईस्ट हिल
फोन : 61188 ● **चंडीगढ़ :** *26. सेक्टर 7- सी, एस.सी.ओ. नं.- 14, 2री मंजिल, मध्य मार्ग फोन : 26735 ● **कोचीन**

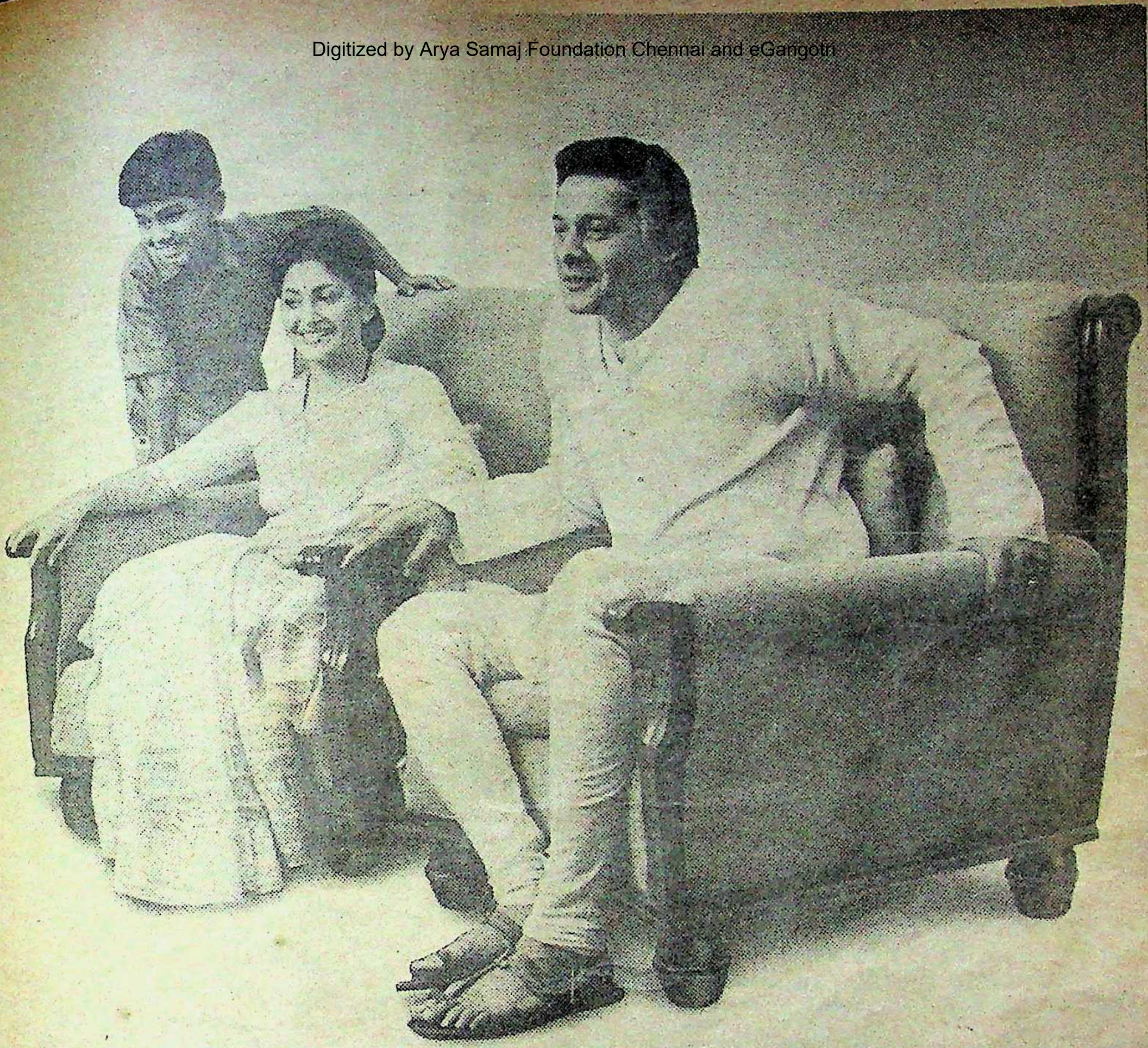

यूरोक्लीन
बहु-उपयोगी सफाई प्रणाली
जो वैक्यूम क्लीनर से कहीं आगे है

अक्वागार्ड
नल की लाइन में जोडा जानेवाला
वाटर फिल्टर-कम-प्यूरिफायर.

यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड
स्वच्छ व स्वास्थ्यकर आधुनिक उपायों में अग्रसर.

*27. XXXV/1448-2, नदनम्, चर्च लैंडिंग रोड, एर्नाकुलम. फोन : 352736/362752 • कोयम्बतूर : *28. नम्बर 6* [illegible] स्वामी रोड, आर.एस. पुरम्, फोन : 43180 • देहरादून : 29. 3, एस्टली हॉल • धनबाद : 30. बिन्दा [illegible] रोड • फरीदाबाद : 31. हाऊस नं. 328, सेक्टर न. 16ए. फोन : 22645 • गाजियाबाद : 32. 41, [illegible] फोन : 40359 • गोवा : 33. शांति निकेतन, इन्डोर स्टेडियम के पास, मिरामार, पणजी. फोन : 6867 • हुबली : *34. [illegible] नं 4569-बी, हुबली धारवार म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन नं. पी. 28/1, वार्ड नं 11, विद्या नगर • हैदराबाद : *35. 403, कला पेशन, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद फोन : 844128/848572 *36. न. 10, तल मंजिल, [illegible] • जयपुर : *37. 22-23, सेंट्रल मार्केट, बापू नगर. फोन : 70205 • जालन्धर : * 38. द्वारा होटल [illegible] नरेन्द्र थियेटर के पास • जम्मू : 39. 39, ए/सी, नल मंजिल, गांधी नगर. फोन : 42586 • जमशेदपुर : *40. [illegible] बिल्डिंग, 1 इनर सर्कल रोड, सी ब्लाक, पी.ओ. बिस्तिपुर. फोन : 24470 • जोधपुर : 41. 39, [illegible] नेहरू पार्क • कोट्टयम : *42. तल मंजिल, जनता टिम्बर बिल्डिंग, एस.एच.एम.पी.ओ. नागमपड्म् • कानपुर : 43. [illegible] 414 सेक्टर बी, महानगर. फोन : 77296 • लुधियाना : *44. 23, रेड क्रास भवन, द मॉल •

मदुरै : *45. 290, के.के. नगर, फोन : 45328 मंगलूर : *46. 3-33-2951/52 पिन्टोज लेन, कद्री कंबला. फोन : 32445 • मैसूर : 47. 443/1 रामास्वामी सर्कल, चामराज डबल रोड. फोन : 27124 • पुणे : *48. मुबारक मंजिल, 1, ढोले पाटिल रोड. फोन : 667968/668773 • रांची : 49. लोअर पीपी कम्पाउंड, गुरू नानक स्कूल के पीछे -फोन : 27681 • सेलम : 50. 19-सी, सारदा कॉलेज रोड • श्रीनगर : 51. सोलर हाऊस, 2री मंजिल, जीरो ब्रिज के पास, राज बाग. फोन : 79935 • सूरत : *52. 31, विजय नगर एनेक्स रिंग रोड, मजूरा गेट. फोन : 54224/53200 53. कृष्ण कृपा, 2री मंजिल, जवेरी सड़क, नवसारी. *54. 9-सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट्स एक्स्टेंशन बिल्डिंग, अठ्वा लाइन्स • तिरूचिरापल्ली : *55. "कावेरी," 79/80, राजा कालोनी, संगम होटल के पीछे, कन्टोनमेंट. फोन : 41867 • त्रिवेन्द्रम : * 56. टी.सी. न 42/88, पकुजा भवन, कलिपांकुलम रोड, मनक्काड. फोन : 79570 • विजयवाड़ा : *57. 33-13-14 वेनेगल्लवारी स्ट्रीट, सीतारामपुरम. फोन : 65964/66742 • विशाखापटणम : *58. 50-50-46, बालैया शास्त्री ले आऊट, सीतामाधरा (पश्चिम). मारिया रेड कॉन्वेन्ट के सामने. फोन : 53009/53010.

everest/89/EFL/188 R1 hn

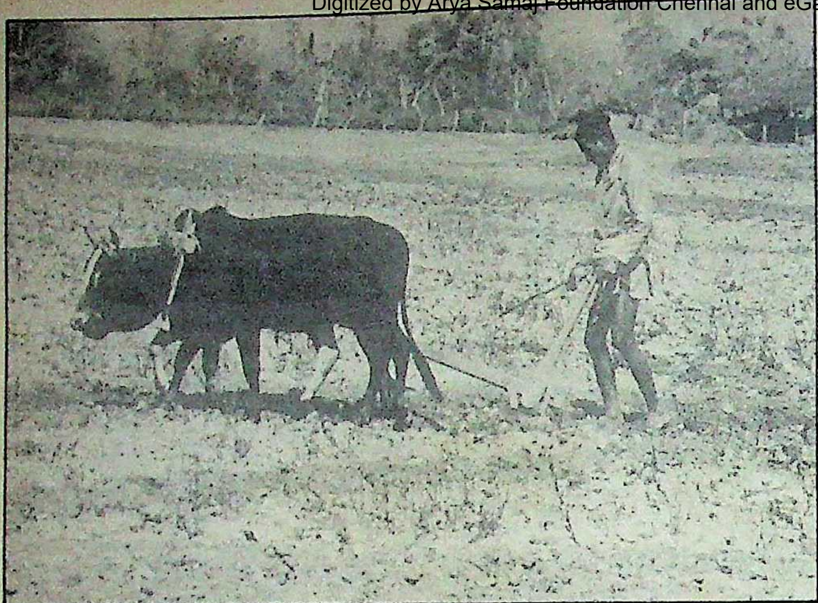

खाद की खेप बंद: नेपाल का कृषक

रहता है। जबकि वर्तमान सरकार किसी भी राजनीतिक दल को सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहती। सरकार इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि भारत की पूर्ण लोकतंत्र की हवा नेपाली जनता को भी प्रभावित किये बिना न रहेगी तथा नेपाल में निर्दलीय पंचायती व्यवस्था तहस-नहस हो जायेगी। इसीलिए नेपाल में ६० से अधिक भारतीय पत्र-पत्रिकाओं पर भी पाबंदी लगा दी गयी है।

आसार अच्छे नहीं : बहरहाल, नेपाल को अपनी गलती का अहसास है या नहीं इस संबंध में फिलहाल कुछ कहना तो तर्कसंगत नहीं है, किंतु हाल में गुटनिरपेक्ष देशों के बेलग्रेड में आयोजित सम्मेलन में नेपाल नरेश बीरेंद्र की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात तथा एक-एक घंटे की लंबी मैत्रीपूर्ण वार्ता का भी कम महत्व नहीं है। हालांकि इस वार्ता का परिणाम तो कुछ भी सामने नहीं आया, किंतु दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की मुलाकात भारत-नेपाल के बीच बिगड़ गये संबंधों के अंधेरे में आशा की किरण जरूर है।

—ब्रह्मानंद मिश्र, काठमांडु से

आज का नेपाल

रायल नेपाली एअरलाइंस बोइंग से काठमांडु के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कुछ बदला हुआ महसूस नहीं होता। आज भी हवाई अड्डे पर चहल-पहल तथा रौनक पहले जैसी ही है। किंतु पर्यटक जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर आकर कहीं जाने के लिए वाहन तलाश करता है, उसे सब कुछ बदला हुआ लगने लगता है। स्थिति यह है कि काफी देर तक तो वाहन उपलब्ध नहीं होते और यदि मिल भी जाते हैं, तो मात्र पांच या छह किमी की दूरी का ८० रुपया किराया मांगा जाता है। इसके बाद काठमांडु में प्रवेश करते ही भारत-नेपाल संबंधों के बिगड़ने से नेपाल में आये संकट का आभास होने लगता है।

वैसे तो शहर में सभी दुकानों तथा मशहूर बाजारों में विदेशी सामान भरे हुए दिखते हैं, किंतु हर चेहरे पर एक अजीब-सी निराशा की झलक भी दिखायी देती है। भारत-नेपाल संबंध बिगड़ने के बाद सबसे पहले संकट आया मध्यवर्गीय घरेलू महिलाओं पर जो भारत द्वारा भेजी गयी गैस पर भोजन बनाने की आदी थीं। मिट्टी के तेल का स्टोव तथा हीटर के इस्तेमाल से झल्लायी निर्मला तमंग ने 'माया' से कहा, "चूंकि हमारे राजनीतिज्ञों को तो चूल्हा फूंकना नहीं होता, इसलिए उन्हें इस बात की क्या परवाह कि महिलाओं पर क्या गुजर रही है? फिर राजनेताओं के परिवार को तो इस तरह का कोई संकट है नहीं।" हालांकि एक नेपाली मंत्री इस बात को काटते हुए कहते हैं, "सच तो यह है कि सिर्फ एक प्रतिशत नेपाली आबादी ही गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। इसलिए गैस की समस्या सरकार के लिए उतनी चिंताजनक नहीं, जितनी परिवहन तथा व्यापार की है।"

बात किसी हद तक सही भी है। नेपाल में उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं। अंडा २४ रुपए दर्जन बिक रहा है, मीट ८० रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है तथा पेट्रोल प्रति लीटर १६ रुपए में उपलब्ध हो पाता है। यही नहीं, चूंकि रिश्ते बिगड़ने के कारण नेपाल की सैर करने वाले भारतीय पर्यटकों में कमी आयी है इसलिए होटल— व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा चूंकि नेपाल में उपलब्ध 'विदेशी माल' ७५ प्रतिशत भारतीय खरीदते थे, इसलिए इस धंधे में लगे लोगों के सामने भी संकट गहरा गया है। दुकान सामानों से जरूर भरी पड़ी हैं, लेकिन खरीदार मुश्किल से नजर आता है।

नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर गणेश बहादुर थापा ने 'माया' को बताया, "निस्संदेह मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरू के आठ महीनों में आर्थिक व्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिले थे, किंतु हाल के संकट ने अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे ढकेल दिया है। अर्थव्यवस्था पर आये संकट को सीमित रखने के लिए नेपाल सरकार ने नेपाली रुपयों के भारतीय रुपयों में बदले जाने की सीमा अधिकतम ५,००० रुपए कर दी है। किंतु दूरवर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करा पाने में अभी सरकार को महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है।" यही नहीं, राष्ट्रीय पंचायत के सूत्रों ने 'माया' को बताया कि कैलाली, प्यूथान तथा मोहत्तरी जिलों में नमक, चीनी तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति अवरुद्ध है। इसी तरह मुस्तांग जिले में अनाज के लिए त्राहि-त्राहि मची है तथा रोल्पा में बीज तथा खाद का अभाव है। सनसारी जिले में तो आज तक भूकंप पीड़ितों लोगों को राहत नहीं पहुंच सकी है। इसी तरह छितवां जिले में बाढ़ से पीड़ित लोगों को दुबारा बसाया तक नहीं गया है।

नेपाल के मौजूदा संकट को मद्देनजर रखकर यह सवाल खड़ा होता है कि अब तक नेपाल जो वस्तुएं भारत को निर्यात कर रहा था आखिर अब वे कहां जा रही हैं? सूत्रों के अनुसार नेपाल ट्रेड प्रमोशन सेंटर नेपाली निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढ़ रहा है। सेंटर के एक प्रवक्ता के अनुसार बांग्लादेश तथा पाकिस्तान नेपाल की दालों, अदरक, घी, मसाले तथा जड़ी-बूटियों के लिए विश्वसनीय बाजार साबित हो सकते हैं। इसी तरह नेपाल में पैदा हुई दालें भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, खाड़ी देशों आदि में भी भेजी जा सकती हैं। बहरहाल, नेपाली सरकार तो हर तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयासरत है, किंतु नेपाल की जनता, विशेष तौर पर मध्यम वर्ग नेपाल के 'आज' से चिंतित है। शायद अपनी इसी परेशानी को व्यक्त करते हुए एक छोटे दुकानदार ने 'माया' से कहा, "हमें उम्मीद है कि नेपाल तथा भारत 'कौन बड़ा, कौन छोटा' की लड़ाई का शीघ्र अंत करेंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञों के इस युद्ध में हम अनावश्यक पिस रहे हैं।"

—काठमांडु से कामाक्षी महिवाल

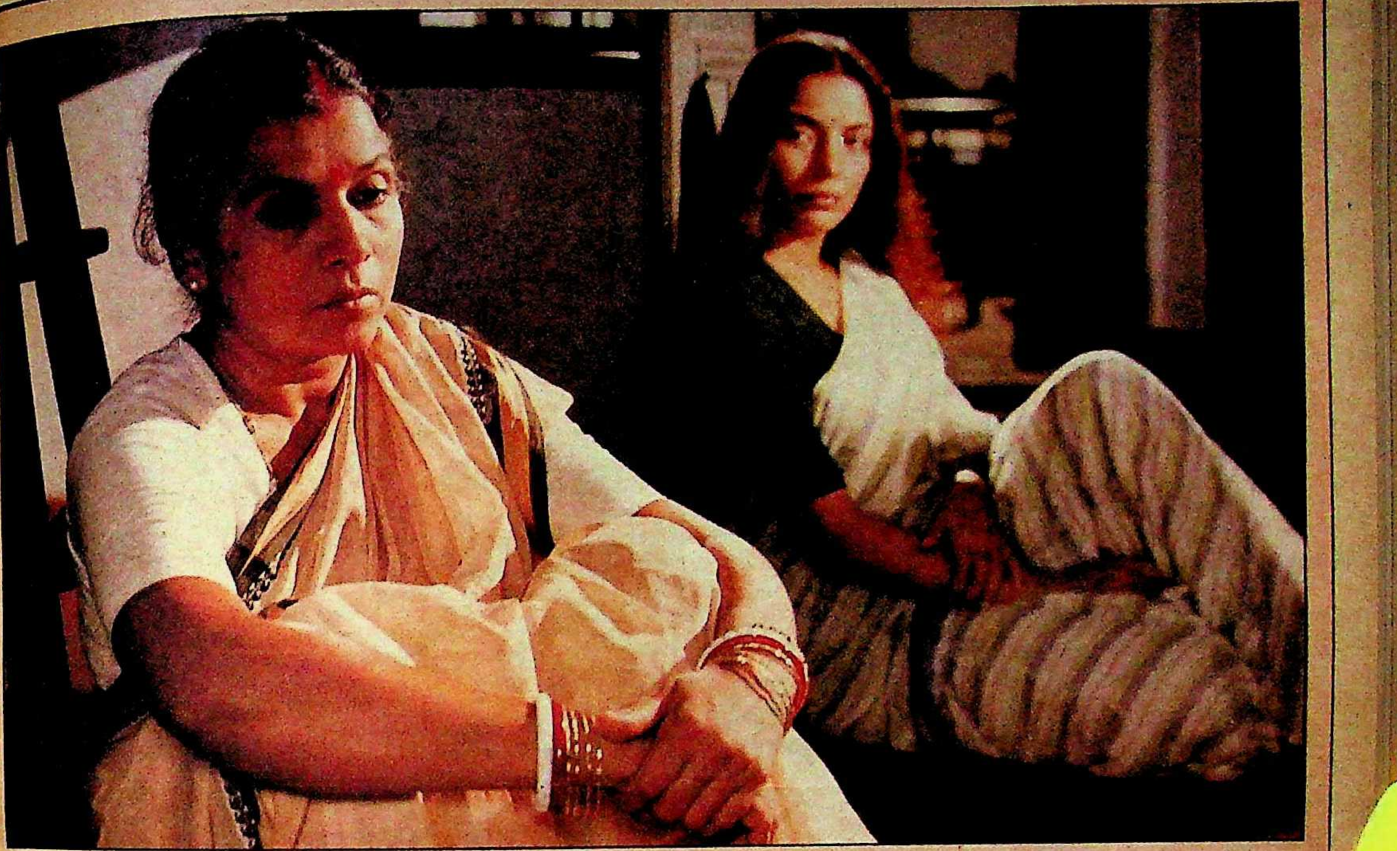

'एक दिन अचानक' में उत्तरा बावेकर और शबाना आजमी

कलात्मक फिल्में

इंतजार के लिए बाध्य क्यों ?

"जब बड़े बजट की बड़े सितारोंवाली भव्य फिल्में बाक्स आफिस पर पिटकर फिल्म इंडस्ट्री को संकट में डाल देती हैं, तो कम बजटवाली सुरुचिसंपन्न फिल्में ही इस संकट से निजात दिलाती हैं और फिल्म निर्माण को नयी दिशा भी प्रदान करती हैं।" काफी दिनों तक व्यावसायिक फिल्मों से जुड़े रहने के बाद अब छोटे बजट की कलात्मक फिल्में बना रहे नरेंद्र गोयल जब यह बात 'माया' से कहते हैं, तो उनके समर्थन में तमाम हाथ उठ पड़ते हैं। ताशकंद तथा कार्लोवीवेरी आदि फिल्मोत्सवों में बहुचर्चित फिल्म 'उपरांत' के निर्माता-निर्देशक मोहन हरि मानते हैं—"इस समय कई बेहतरीन फिल्में बनकर तैयार हैं, जो वितरकों और सिनेमाघरों के अभाव में डिब्बों में बंद पड़ी हैं। अगर कुछ लोग आगे बढ़कर इनके प्रदर्शन की व्यवस्था करें, तो संभव है ये ही फिल्में मौजूदा संकट से फिल्म इंडस्ट्री को उबार सकती हैं।"

दो दशक पूर्व भी ऐसा ही संकट आया था फिल्म इंडस्ट्री पर, तब 'भुवनशोम' (मृणाल सेन), 'अनुभव' (बासु भट्टाचार्य), 'मेरे अपने' (गुलजार) ने प्रमुख भूमिका निभायी थी। बाद में 'अर्थ' (महेश भट्ट) तथा 'उमराव जान' (मुजफ्फर अली) भी काफी मददगार साबित हुई थीं। इत्तिफाक से इन्हीं फिल्मकारों की नयी फिल्में पूरी होने के बावजूद आज सिनेमाघर तक नहीं पहुच पा रही हैं। मृणाल सेन (एक दिन अचानक), बासु भट्टाचार्य (पंचवटी), गुलजार (लिबास तथा लेकिन), महेश भट्ट (स्वयं), मुजफ्फर अली (जूनी) के अलावा अमित खन्ना (शेष), नबेंदु घोष (तृषाग्नि) तथा मोहन हरि (उपरांत एवं अभिशाप) विदेशी फिल्मोत्सवों में काफी चर्चा तथा श्रेष्ठता के तमगे बटोरने के बावजूद अपने ही घर (देश) में कुछ अदद सिनेमाघरों के दरवाजे खुलने के इंतजार में दिन काट रहे हैं। ऐसे में मोहन हरि का यह सवाल उठाना जायज ही है कि जब वितरक और प्रदर्शक व्यावसायिक जोखिम के डर से बड़ी फिल्मों को हाथ नहीं लगा रहे हैं और फिल्मों के अभाव में सिनेमाघरों पर तालों के लटकने की स्थिति आ गयी है, तो कम बजटवाली इन फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा जोखिम के संकट को कम क्यों नहीं किया जाता?

यहां ऐसी फिल्मों की ही चर्चा की जा रही है, जो अपने भीतर फिल्म निर्माण तथा तकनीक का एक नया अध्याय छिपाये हुए हैं। इन फिल्मों में रिश्तों को बड़ी गहराई से कुरेदने की कोशिश इन फिल्मकारों ने की है। इस प्रयास में उन्होंने रिश्तों के तमाम त्रासदीजनक पहलुओं को उजागर किया है। 'एक दिन अचानक', 'पंचवटी', 'स्वयं' तथा 'जूनी' जहां रिश्तों की तस्वीरें अपनी नायिकाओं के माध्यम से पेश करती हैं, वहीं 'शेष', 'तृषाग्नि' तथा 'लेकिन' सचाइयों के रिश्ते की कुछ और तस्वीरें पेश करती हैं जिनमें से कुछ भयावह हैं, तो कुछ त्रासदीदायक।

'एक दिन अचानक' : महानगरीय जिंदगी का अभिशाप : 'भुवन शोम' से लेकर 'खडहर' तक

मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास कुन्डम गाँव। शाम ढले, जब पंछी अपने नीड़ की ओर लौटते हैं, सुशीलाबाई भी अपने कर्मवीर पति की वापसी की राह देखती हुई अपनी नन्हीं-मुन्नी रजनी को बहलाती है। उसका नन्हा बेटा बलराम भी गौओं के साथ खेलता-कूदता लौटने वाला है। नन्हीं रजनी की किलकारियाँ उसे उस वक्त की याद दिलाती है... आज से ९ साल पहले जब उनका नया-नया ब्याह हुआ था और उन्होंने परिवार कल्याण के लिए नियोजन का संकल्प लिया था, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल रहे। आई टी सी ने उन्हें राह दिखायी...

कुन्डम की सुशीलाबाई। नये ब्याह के हुलास के साथ इन्हें चिन्ता थी कि इनकी नियति छः बच्चों के बोझ से थकी-टूटी इनकी माँ जैसी न हो।

तभी आई टी सी के माध्यम से इनके पति ने परिवार नियोजन साधनों को अपनाया।

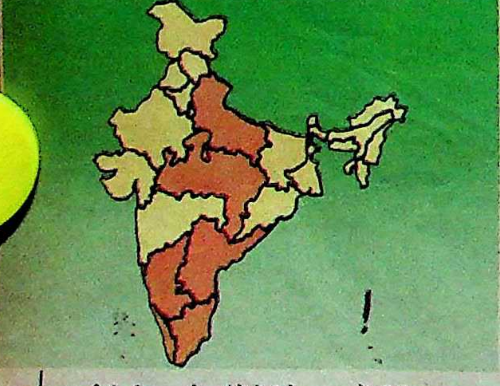

आई टी सी भारत के गाँवों में निरोध साधनों की वितरक।

भारत में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के सहयोग से कुन्डम ग्रामीण सामूहिक परियोजना की तहत आई टी सी पारम्परिक अंधविश्वासों को जड़ से मिटाकर मातृत्व और बाल-स्वास्थ्य को लोकप्रिय बना रहा है। भारत के कोने-कोने में फैले विशाल वितरण व्यवस्था और मार्केटिंग तजुर्बों के दम पर आई टी सी सन् १९६८ से निरोध साधनों का प्रचार कर रही है।

जिन क्षेत्रों में समूचे देश की आधी से ज्यादा आबादी बसी है, सन् १९८९-९० में आई टी सी इस परियोजना के माध्यम से जन-शक्ति प्रशिक्षण और निरोध साधनों के प्रचार-वितरण पर १ करोड़ से भी ज्यादा रुपये खर्च करेगी।

देश भर में निरोध साधनों की सबसे बड़ी वितरक के रूप में आई टी सी के अथक प्रयासों को समुचित इनाम भी मिला है—परिवार कल्याण के क्षेत्र में सन् १९८८ का एफ आई सी सी आई पुरस्कार। यह एक ऐसे सम्मान का प्रतीक है, जो सैकड़ों-हजारों परिवारों के लिए सुरक्षित भविष्य और खुशहाली का संदेश देता है।

शिक्षण
१ करोड़
ड़ी
यासों
कल्याण
ी आई
है, जो
विष्य

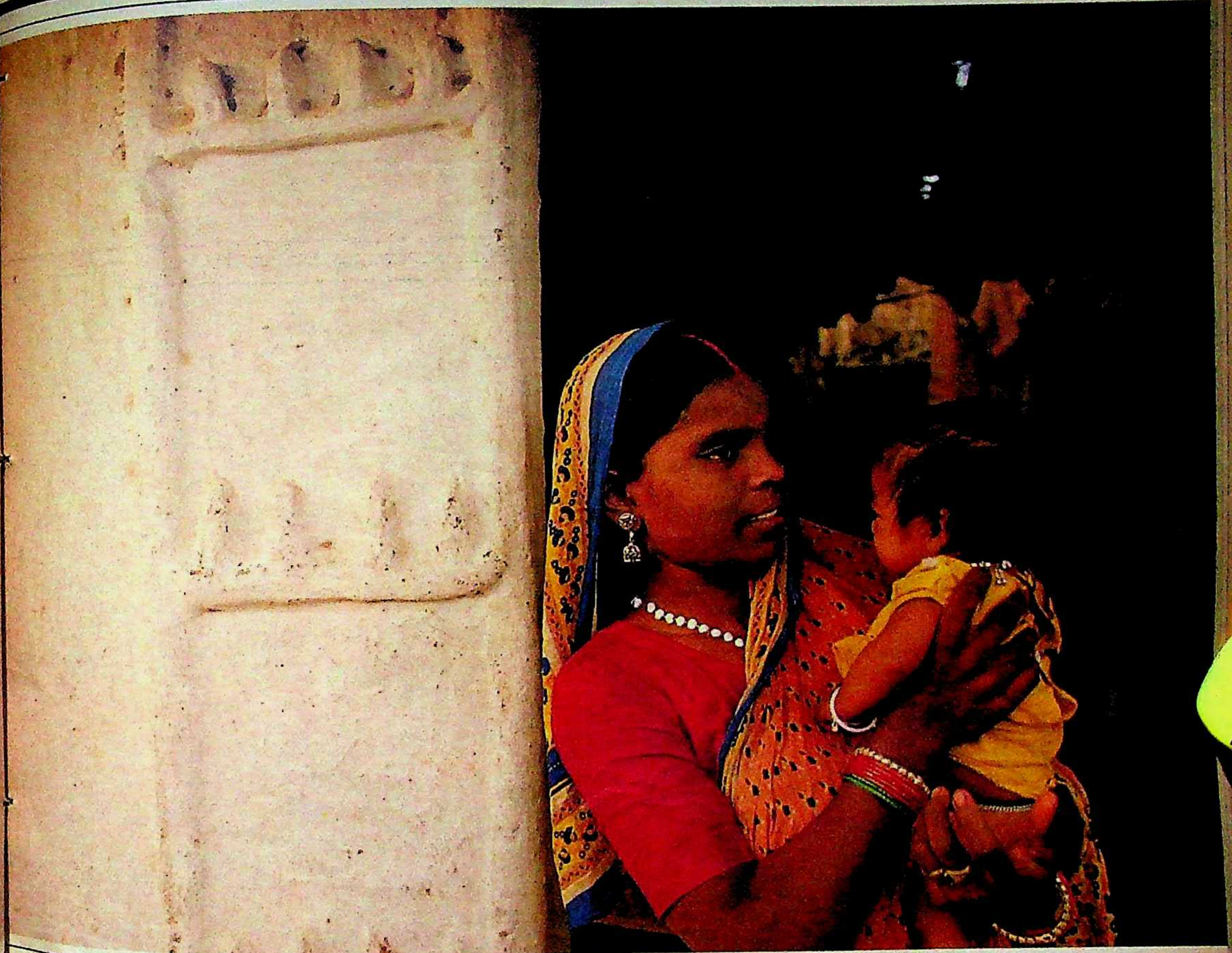

आई टी सी भारत के लिए और कहाँ-कहाँ कार्यरत है?

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हज़ारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी। खाद्य-अखाद्य तेलों एवं सहायक उत्पादनों के निर्माण और मार्केटिंग के साथ-साथ, आई टी सी ने आयात भी कम किया है।

कुटीर उद्योग : हथकर्घे, कच्चे माल और तकनीकी विशिष्टताओं के दम पर आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिये शाहजहांपुर की प्राचीन कालीन-बुनाई कला को पुनर्जीवित किया है। अब कालीनों के साथ-साथ अन्यान्य लघु और कुटीर उद्योगों की सामग्रियाँ भी आई टी सी द्वारा निर्यात की जाती हैं।

पेपर और बोर्ड — कोर सैक्टर में : आई टी सी द्वारा विकसित भद्राचलम पेपरबोर्ड्स अपने क्षेत्र में अग्रणी है। इसने रिकॉर्ड उत्पादकता के साथ साथ वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी कल्याण के प्रति गहरी जागरूकता का नया मानदंड स्थापित किया है।

I.T.C. Limited

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

Contract ITC 58.89 HIN.R

'स्वयं' में इला अरुण, सोनी राजदान और वहीदा रहमान

की अपनी लंबी फिल्म यात्रा में मृणाल सेन ने जिंदगी की यथार्थता को पूरी सचाई के साथ उकेरने का जो प्रयास किया है, 'एक दिन अचानक' उसकी एक नयी कड़ी है।

'एक दिन अचानक' की कथा प्रख्यात बंगला उपन्यासकार रमापद चौधरी के उपन्यास पर आधारित है। पूरी कहानी एक आम मध्यमवर्गीय परिवार के मुखिया (प्रोफेसर) के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्म के प्रारंभिक दृश्यों के बाद वह दुबारा फिल्म के परदे पर नहीं दिखलायी पड़ता। घर में बैठ कर बाहर हो रही बारिश का अच्छा-खासा आनंद लेते-लेते अचानक उसके (प्रोफेसर) मन में न जाने क्या उपजता है कि बारिश थमते ही वह घर से सैर-सपाटे के लिए निकल पड़ता है, फिर कभी वापस नहीं लौटता।

यहां निर्देशक मृणाल सेन एक सवाल उठाते हैं—वह वापस क्यों नहीं लौटता ? उसके परिवार के चारों सदस्य (पत्नी, दो बेटियां तथा एक पुत्र) मानसिक रूप से उसकी गुमशुदगी और तलाश के लिए परेशान भी हैं। प्रोफेसर के वापस न लौटने पर वे समूचे शहर—जहां-जहां भी प्रोफेसर के जाने की संभावना हो सकती है, वहां-वहां जाकर उसे तलाशने की कोशिश करते हैं।

मृणाल सेन यह जानने या बतलाने की जरूरत महसूस नहीं करते कि प्रोफेसर का हश्र क्या हुआ ? "उनका मानना है कि 'यह महानगर में रहने का जन्म-जन्मांतर का अभिशाप है, जहां की भीड़ में कोई भी चेहरा अचानक गुम हो सकता है और लोग उसे सिर्फ अपने रिश्तों के ही कारण तलाशने की जहमत उठाते हैं और अंतत: थक-हार कर अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। मैं तो सिर्फ उनके रिश्ते के जुड़ाव की पर्तों के भीतर झांकने की कोशिश करता हूं।" फिल्म के सभी कलाकार (डा० श्रीराम लागू : प्रोफेसर, उत्तरा बावेकर उनकी पत्नी, शबाना आजमी तथा रूपा गांगुली उनकी बेटियां, अपर्णा सेन : उनकी शिष्या मनोहर सिंह एवं अनिल चटर्जी : अन्य भूमिकाएं

'शेष' में आलोकनाथ एवं अंकिता झवेरी

अपने चरित्रों को पूरी संजीदगी के साथ जीते हैं। बहुत धीमी गति की होने के बावजूद फिल्म दर्शक को पल-पल झकझोरती है।

'पंचवटी' : अकेलेपन का चक्रव्यूह : मृणाल सेन यथार्थवादी फिल्मकार हैं, इसलिए वे मानवीय संबंधों पर तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन उन्हें जज्बाती नहीं बनने देते, जबकि बासु भट्टाचार्य इसे जरूरी मानते हैं। अपनी पूर्व तीन फिल्मों ('अनुभव', 'आविष्कार' तथा 'गृहप्रवेश') में उन्होंने पति-पत्नी के रिश्तों को विभिन्न कोणों से पेश किया था।

'पंचवटी' दांपत्य जीवन में आ जानेवाली उस एकरसता और खालीपन को भरने की कथा है जिसके शिकार अलग-अलग माहौल में जी रहे दो युगल दंपती हैं। चित्रकार साध्वी (दीप्ति नवल) दांपत्य जीवन में जिन संवेगात्मक अनुभूतियों की तलाश करती है, उसे उसका पति यतिन (अकबर खान) नहीं दे पाता। वह अच्छा इंसान है, पति के सारे कर्तव्यों को पूरी तरह निभाता है तथा पत्नी एवं परिवार के प्रति एक आम पति की तरह निष्ठावान भी है, लेकिन पत्नी के सौंदर्य को सराह नहीं पाता। न ही अपनी पत्नी को वह मानसिक साहचर्य दे पाता है। ठीक ऐसे में नेपाल से आया कवि हृदय विक्रम (सुरेश ओबेराय) साध्वी की जीवन-शैली और उसके सारे पारंपरिक मूल्यों का कायापलट कर देता है। मानसिक साहचर्य की तलाश में भटक रही साध्वी विक्रम के साहचर्य में, अपने दांपत्य जीवन में आ गयी समूची एकरसता से निजात पा जाती है—वह अपने पति यतिन से न तो प्रेम कर पाती है और न ही घृणा, दूसरी तरफ वह विक्रम के प्रति समर्पित होने, उसके बच्चे की मां बन जाने के बावजूद यतिन से तलाक ले कर विक्रम से विवाह कर लेने का साहस नहीं जुटा पाती, फिर भी बसा-बसाया घर-परिवार छोड़ कर वह विक्रम के साथ नेपाल जाने के लिए तैयार हो जाती है।

'पंचवटी' में दीप्ति नवल

साध्वी की ही तरह विक्रम भी दांपत्य जीवन में व्याप्त एकरसता का शिकार है। उसकी पत्नी नीरा (अनुराधा) को क्लब, पार्टियों-समारोहों से फुरसत नहीं। अपने एकाकीपन को प्रकृति, कविता, पेंटिंग्स तथा पौधों की दुनिया में बिताने को विवश विक्रम को यही बातें साध्वी के निकट ले आती हैं। अपनी-अपनी भौतिक जिंदगी में जी रहे नीरा और यतिन को तब होश आता है जब बहुत कुछ खतम हो जाता है। इस तरह चार अलग-अलग जिंदगियां अपने-अपने सुख और वैयक्तिकता की तलाश में भटकने को विवश हैं।

'स्वयं' : एकाकीपन से अकेले संघर्ष : जहां 'पंचवटी' दो अलग-अलग जिंदगियों के मानसिक खालीपन तथा खोखले रिश्तों की फिल्म है, वहीं महेश भट्ट की नयी फिल्म 'स्वयं' इंसानी रिश्तों की दीवार को खुद ढाह कर अपने एकाकीपन को भरने के लिए बेचैन एक औरत की कथा है। महेश भट्ट बासु भट्टाचार्य की तरह फिल्म के अंत में कोई प्रश्नचिह्न नहीं खड़ा करते, कहानी का सहज अंत तलाश लेते हैं।

'उपरांत' में रंजना गौर और डाली जेना

४० वर्षों का लंबा दांपत्य जीवन अपराजिता (वहीदा रहमान) को, पति की कैंसर से मौत के बाद, एकबारगी अकेलेपन की दहलीज पर छोड़ जाता है। अपने पति अविनाश (आकाश खुराना) के बेहतरीन इलाज के लिए वह घर का सारा कुछ बेच या गिरवी रख देती है। उसकी सभी जरूरतों की पूर्ति तथा देखभाल के लिए उसकी दोनों बेटियां (सोनी राज़दान, इला अरुण) और दामाद (अवतार गिल, महेश आनंद) उसे हर तरह का सहारा देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सहायता को वापस कर वह अपने अतीत और एकाकीपन की खोल में ही कैद रहना चाहती है। छोटी बेटी नंदिनी (सोनी राजदान) उसे जबरदस्ती घर लाती है, लेकिन उसे उसके मानसिक एकाकीपन से मुक्त नहीं करा पाती। ऐसे में उसकी सहायता के लिए फादर मारिस (अजंता देसाई) आते हैं जिनके स्कूल में पढ़नेवाले एक अनाथ अंधे बच्चे (आकर्षण खुराना) को उसके पति की आंखें दे दी जाती हैं। खाली समय को काटने के लिए वह उसी स्कूल में काम करने लगती है। दरअसल, फिल्म वहीं खतम हो जाती है जब अनाथ बच्चे की आंखों में उसे अपने पति की आंखें दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन महेश भट्ट इसके बाद की उसकी अकेलेपन से जूझने की कथा को पेश करना चाहते थे। 'स्वयं' वहीदा रहमान की अभिनय की दृष्टि से श्रेष्ठतम फिल्मों में से एक है।

'शेष' : मौत का साक्षात्कार : 'स्वयं' की अपराजिता की तरह ही 'शेष' की माया (अनीता कंवर) को भी वैधव्य के हादसे से गुजरना पड़ता है और उसे भी अपने आपको प्रतिक्षण निकट आती पति की मौत का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ता है। लेकिन वह अपराजिता की तरह मानसिक टूटन का शिकार नहीं होने पाती, क्योंकि खालीपन की जिंदगी तनहा गुजारने और एकाकीपन से जूझने की उसकी मजबूरी अपराजिता जैसी नहीं है।

एक उच्च अधिकारी संजय (आलोक नाथ) तथा विज्ञापन एजेंसी में काम करनेवाली अधिकारी माया (अनीता कंवर) इसलिए आदर्श दंपती माने जाते हैं कि वे पारंपरिक तथा आधुनिक जीवन-शैली के तालमेल से अपनी खुद की जिंदगी जीते हैं जहां न तो सिद्धांतों और सोचों का टकराव होता है, न ही रिश्तों में दरार की गुंजाइश। वे हमेशा की तरह अपने विवाह की वर्षगांठ तथा दिवाली मनाने अपने माता-पिता के पास, हास्टल में रहनेवाली अपनी बेटी छुटकी (अंकिता झबेरी) के साथ, दिल्ली आ आते हैं। दिवाली की रात अजय को अचानक उठे दर्द की जांच के बाद जब डाक्टर उसको कैंसर (लिंफोब्लास्टिक लिम्फोमा) और चंद दिनों का मेहमान बतलाते

हैं, तो एक हंसते-खेलते परिवार पर जैसे प्रकृति का गाज गिर पड़ता है। ये क्षण माया के लिए बेहद चुनौती भरे साबित होते हैं। लेकिन वह आम पत्नियों से अलग है, इसलिए निश्चय करती है कि अजय की आसन्न मौत और खतरनाक बीमारी का कोई भी मातम घर में नहीं मनाया जायेगा। वह समूचे घर और वातावरण में खुशियों के एक नये संसार का निर्माण करती है, ताकि अजय पल-पल निकट आती मौत से भयभीत एवं तनावग्रस्त होने के बजाय उसका हंसते हुए साहस से सामना कर सके। 'बुनियाद' (सीरियल) के बाद अनीता कंवर तथा आलोकनाथ संभवतः पहली बार इतने प्रभावशाली रोल में आये हैं।

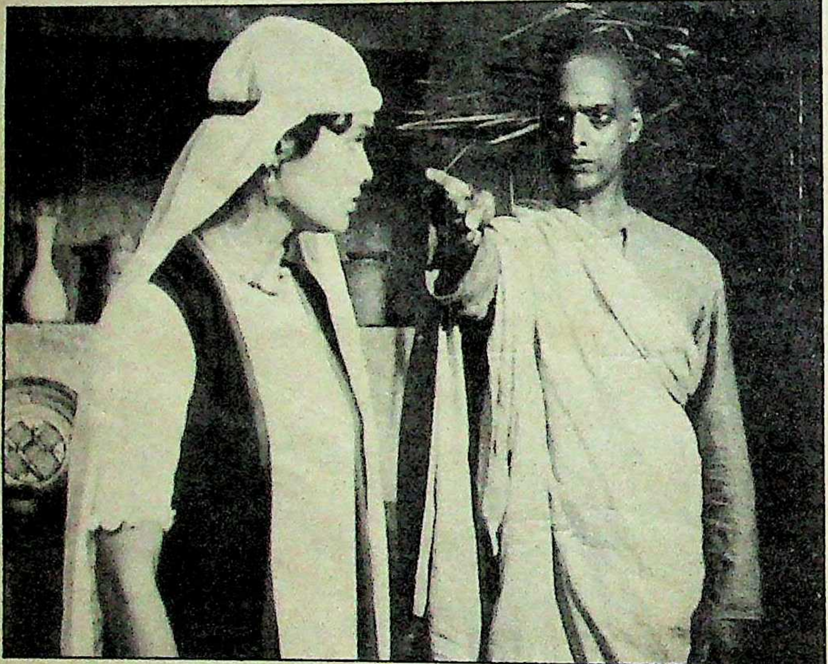

'तृषाग्नि' में पल्लवी जोशी और नाना पाटेकर

'तृषाग्नि': रिश्तों की निर्वैयक्तिकता को उजागर करनेवाली 'तृषाग्नि' (निर्माता-निर्देशक : नबेंदु घोष) एक विराट रेगिस्तान के बीच बसे सटीपुट नामक छोटे-से शहर में ले जाती है जो अचानक आये भीषण चक्रवात में नष्ट हो जाता है और सिर्फ बचता है बौद्ध विहार तथा उसमें रह रहे विहार प्रमुख पिथुमिट (आलोकनाथ) एवं उनका शिष्य उचंड (नाना पाटेकर)। उनके अलावा उस चक्रवात में दो शिशु और शेष बचे थे, जिन्हें पिथुमिट ने अपनी शरण में रख कर पालना-पोसना शुरू किया और उनके नाम रखे-निर्वाण एवं इति।

२० वर्षों बाद निर्वस्त्र स्नान करती किशोर इति (पल्लवी जोशी) को देखकर उचंड के मन में बुराइयों के आगमन का अहसास होता है और बार-बार उसे बुराइयों का सम्राट मारा मानसिक तौर पर उद्वेलित करता है। मारा ने भगवान बुद्ध की तपस्या भंग करने के लिए अपनी तीन रूपसी कन्याओं को भेजा था। बुराइयों के साथ-साथ उचंड के मन में सेक्स, ईर्ष्या की प्रचंड आंधी भी जन्म लेती है जिसका शिकार बनते हैं निर्वाण (नितीश भारद्वाज) और इति। इति का निर्वस्त्र स्नान करने का दृश्य बार-बार उचंड के मन में आकर उसे आहत करता है और वह विहार के नियमों का फायदा उठाकर दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की तरकीबें रचता है और निर्वाण को संन्यासी बनवा देता है, ताकि वह इति को न पा सके। निर्वाण और इति के प्रति स्नेह और सहानुभूति रखने के बावजूद वृद्ध पिथुमिट उचंड की साजिशों के सामने खुद को असहाय पाते हैं। यहां तक कि वे उन दोनों को भोजन-पानी से मरहूम कर देने, फिर उस सुदूर रेगिस्तान में उन्हें विहार से निकाल देने के उचंड के निर्देश का प्रतिरोध भी नहीं कर पाते। अंततः उचंड को अपनी गलतियों का अहसास होता है और वह उन्हें वापस लाने के लिए निकलता भी है, लेकिन २० वर्ष पूर्व-सा चक्रवात पुनः आकर सब कुछ ध्वंस कर जाता है।

नबेंदु घोष इसे त्रिपक्षीय रिश्तों की भी फिल्म मानते हैं जिसकी एक धुरी पर महानता की हद को छूनेवाले पिथुमिट हैं, जो विहार-प्रमुख होने के बावजूद विवश हैं, तो दूसरी धुरी पर विद्वान, विवेकी लेकिन ईर्ष्या की आग में जल रहा उचंड है तथा तीसरी धुरी पर प्रेम की कोमल अनुभूतियां संजोये निर्वाण एवं इति हैं। उनके प्रति पिथुमिट का रिश्ता पितृवत एवं गुरुवत है, लेकिन उचंड का रिश्ता साजिशों की पिरामिडों पर स्थापित है। फिर निर्वाण और इति का एक अलग रिश्ता जिसकी खातिर वे नियमों एवं परंपराओं के वि विद्रोह कर बैठते हैं।

'उपरांत': 'तृषाग्नि' की इति शोषण शिकार नहीं होने पाती, लेकिन मोहन हरि फिल्म 'उपरांत' की फुलिया (रंजना गौर) सामंतवादी तंत्र के शोषण की कदम-कदम शिकार होती है जिसने बंधुआ मजदूर प्रथा सदियों-पूर्व जन्म दिया था।

बंधुआ मजदूर हीरालाल (मका देशपांडे) की अपने स्वामी ठाकुर (सुधीर पां के प्रति अटूट निष्ठा है, लेकिन ठाकुर के लि हीरालाल और उसकी युवा पत्नी फुलिया पाले जानवर से कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखते, इसीलि फुलिया ठाकुर से लेकर पटवारी (अशोक शर्मा और उसके अमलों के दैहिक शोषण का शिका होती रहती है और हीरालाल मशीन की तर अपनी पत्नी के शोषण और जमीन के हथिया ने की ठाकुर की कारस्तानियों को देखने के लि मजबूर है। इस समूचे अन्याय-तंत्र में मुनी (महेश तोमर) तथा ठकुराइन (आभा मिश्रा की उसके प्रति सहानुभूति तो है, लेकिन वे उसकी मदद करने में असमर्थ हैं। दूसरी तर ठाकुर की युवा बेटी सरला (सुनीला सिंह सेक्सुअल फंतासी का शिकार बन जाती है। अंत बंधुआ शोषण से हीरालाल और फुलिया को मौ ही मुक्ति दिला पाती है।

दरअसल, फिल्म यहां खतम नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है। फुलिया औ हीरालाल की दर्दनाक मौत के बाद हवेली भीतर अनहोनी घटनाओं का क्रम शुरू हो जा है—ठाकुर की मां सीढ़ियों से फिसल कर गि पड़ती है, भैंसों के थन सूख जाते हैं, जमीनों गलत इंदराज किये हुए दस्तावेजों से भरा पटवा का बस्ता गायब हो जाता है, ट्रांस में मर कामांध पटवारी के कमरे में पहुंच जाती है फि सारी हवेली धू-धू कर जलने लगती है।

मोहन हरि शोषण के विरुद्ध विद्रोह आग नहीं जलाते, क्योंकि आज के जमाने कायरता की जिंदगी जीनेवाले लोग शोषक विरुद्ध हथियार उठाने का साहस नहीं रखते इसलिए वे अंधविश्वासों का सहारा लेते हैं। उन लिए यह अंधविश्वास ही शोषण के विरुद्ध क्रां का प्रतीक है।

ये सभी फिल्में उत्कृष्ट निर्देशन, चु पटकथा, कलाकारों के सशक्त एवं जीव अभिनय, मनोरम छायांकन तथा सार्थक संगीत भरपूर होने के कारण वर्तमान फिल्म निर्मा प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती लेकिन असली सवाल उठता है, इनके प्रदर्शन का क्या वितरक इन्हें बंद डब्बों से निकालकर दर्श के सामने लाने में समर्थ होंगे?

—रवींद्र श्रीवास्त

गैरइंका राज्य सरकारों को गिराने की तिकड़म

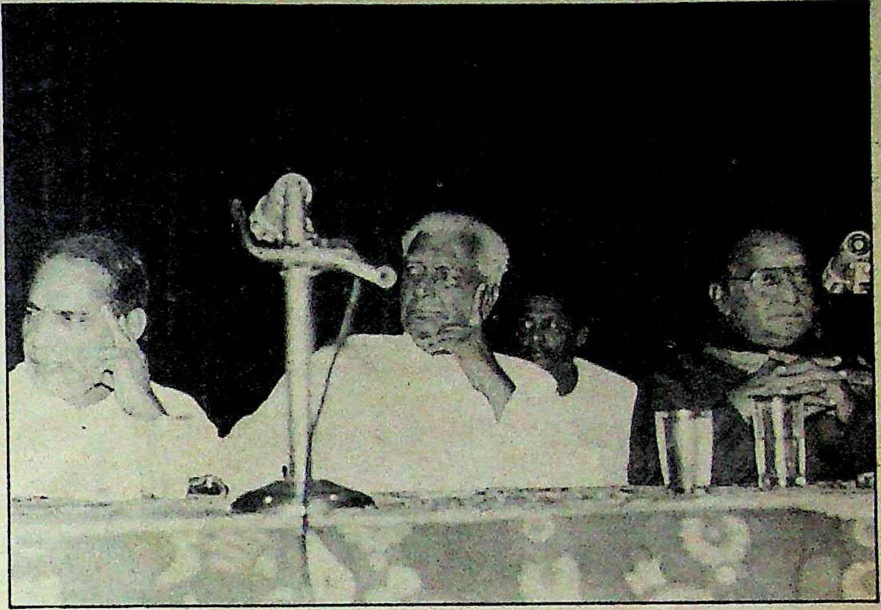

प्रतिकार-चिंतन: रामकृष्ण हेगड़े, देवीलाल और रामाराव

केंद्र और कांग्रेस ने गैरकांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों के खिलाफ हमले तेज कर दिये हैं। प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस आरोप के जवाब में कांग्रेस और केंद्र के प्रवक्ता इसका खंडन करते हैं और कहते हैं गैरइंका सरकारें अपनी अंदरूनी खामियों के कारण ही खस्ताहाल हैं। वास्तविकता क्या है?

आंध्र प्रदेश: नक्सलवादियों की हिंसा को काबू न कर पाने का आरोप लगा कर प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया जाना व मुख्यमंत्री रामाराव का पत्रकार सम्मेलन में अपमान किया जाना। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रामाराव सरकार की बर्खास्तगी की मांग का प्रस्ताव पारित कर इस संबंध में हस्ताक्षर अभियान चला राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाना। मुख्यमंत्री रामाराव को इन समस्त गतिविधियों में आंध्र सरकार को बदनाम कर उसे गिराने की साजिश का प्रयास दिखायी देता है।

हरियाणा: सम्राट होटल (दिल्ली) में व्यवसायी डीगराम द्वारा लगभग एक दर्जन जनता दल विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश। पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थशंकर रे व हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा 'भारत बंद' के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवीलाल को विरोधपत्र लिख संवैधानिक संकट पैदा करने का प्रयास। देवीलाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग के लिए हरियाणा इंका की दिल्ली कूच की योजना। मुख्यमंत्री देवीलाल ने इन हरकतों को 'केंद्र की बदनीयती और तख्तापलट का षड्यंत्र' करार दिया और इसका खुला विरोध किया है।

असम: बोडोलैंड मसले पर दिल्ली में संपन्न वार्ता और हिंसा की रोकथाम के आश्वासनों के बावजूद हिंसक गतिविधियों में तेजी। मुख्यमंत्री महंत व गृहमंत्री फुकन की खुली टकराहट से असम गण परिषद (अगप) में फूट और चरमपंथी दल यूएलएफए की नयी सरगर्मियां। इन घटनाओं को गिनाते हुए मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्रीय गृहमंत्रालय के मंत्रियों—बूटा सिंह और संतोषमोहन देव—पर हिंसा भड़काने और असम सरकार बर्खास्त करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है।

तमिलनाडु: जयललिता द्वारा करुणानिधि सरकार बर्खास्त करने की मांग। 'भारत बंद' की पूर्वसंध्या पर राज्य सरकार को बंद में शामिल न होने के लिए केंद्र का मनोवैज्ञानिक दबाव। केंद्रीय वाणिज्यमंत्री दिनेश सिंह और तमिलनाडु के राजस्वमंत्री मनोहरन की गुपचुप वार्ता। इन सारी गतिविधियों के पीछे पर्यवेक्षकों को तमिलनाडु सरकार गिराने अथवा उसको एकजुट विपक्ष से अलग-थलग करने की मुहिम दिखाई देती है।

नौवीं लोकसभा के लिए चुनाव के चंद महीनों पूर्व केंद्र और विपक्षी सरकारों के मध्य चलते छायायुद्ध के कारण, उद्देश्य और रणनीति सभी स्पष्ट हैं। भरपूर चुनावी लाभ अर्जित करने के लिये केंद्र यदि विपक्ष शासित राज्यों को धर दबोचने की जमीन तैयार करने में जी-जान से जुटा है, तो विपक्षी सरकारों ने उससे लोहा लेने के लिये आसमान सर पर उठा जनमत अपने पक्ष में करने का अभियान छेड़ दिया है। आगामी चुनाव की कांटे की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए दोनों के लिए अपनी-अपनी रणनीति की कामयाबी आवश्यक है। कारण, जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, इसका दारोमदार काफी हद तक इसी सफलता-असफलता पर निर्भर है।

कांग्रेस-इ की चिंता: दरअसल गैरकांग्रेस-इ दलों की एकजुटता और उससे उपजे विपक्ष के बुलंद हौसलों ने सत्ता दल और केंद्र सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बढ़ते-कसते शिकंजों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। अनेक सरकारी-गैरसरकारी जांचों ने यह संकेत दिया है कि यदि विपक्ष एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा करने की अपनी वर्तमान इच्छा और योजना को अमली जामा पहनाने में सफल हो जाये, तो अगले चुनाव में सत्ता दल कांग्रेस के लिये हार का मुंह देखना लाजिमी हो जायेगा।

कुछ समय पूर्व तक सरकार को आशा बंधी थी कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पायेगा। वामपंथ और दक्षिणपंथ के वैचारिक मतभेदों और परस्पर विरोधी बयानबाजी तथा जनता दल में जारी सरफुटौवल से उसे ऐसे आसार दिखने लगे थे कि विपक्ष चार कदम भी आगे नहीं चल पायेगा। लगभग दो वर्ष पूर्व बोफोर्स के मुद्दे के बाद से संसद के भीतर सफल साझा कार्यवाही करनेवाले विभिन्न विपक्षी दलों ने कांग्रेसी मंसूबों पर तब पानी फेर दिया जब वे संसद के बाहर भी एकजुट हो गये। समस्त शिकवे-गिले मिटा सभी विपक्षी पार्टियों के १०४ लोकसभा सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे दे सत्ता दल को सकते में डाल दिया। रही सही कसर ३० अगस्त के 'भारत बंद' ने तब पूरी कर डाली जब कांग्रेस की हर चाल को नाकाम

करते हुए विपक्ष, संसद के बाहर सड़क पर भी एकजुट हो गया। नतीजतन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बाजी अपने हक में करने के लिए कांग्रेस के लिये नई शतरंजी चालें चलना जरूरी हो गया है। जाहिर है, ये चालें उन राज्यों में ज्यादा चली जायेंगी जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं।

ऐसा नहीं कि विपक्ष के मध्य फूट डालने की मुहिम सत्तारूढ़ दल ने त्याग दी हैं। राजनीति के पंडित इस मुहिम की दो ताजा मिसालें पेश करते हैं; एक, प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सांप्रदायिकता के मसले को हर मंच से उठा वामपंथियों—दक्षिण-पंथियों को उनके मतभेदों का स्मरण दिलाया जाना और दूसरा, कांग्रेस के समाजवादी खेमे के अगुआ महासचिव विट्ठल नरहरि गाडगिल द्वारा गत ४ सितंबर को वामपंथी दलों के लिये प्रस्तुत तीनसूत्री सवाल। इसके तहत गाडगिल ने जनता दल के विवादास्पद राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी द्वारा वामपंथियों की भूमिका के मूल्यांकन, उनकी अफगान नीति, और जनता दल-भाजपा-शिवसेना गठजोड़ के (तीन) प्रश्न उछाले हैं। यह चाल राम जेठमलानी की छवि ध्वस्त करने से अधिक वामपंथ को शेष विपक्ष से अलग-थलग करने की मंशा से प्रेरित है।

हानि-लाभ के अनुभव: ऐसी छिटपुट तीरंदाजी के अतिरिक्त विपक्षी किलों पर सीधी गोलाबारी कांग्रेस की वर्तमान युद्ध योजना का एक अहम कोण है। इसके तहत विपक्ष शासित राज्यों-विशेषकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम और तमिलनाडु-पर सीधा धावा बोला गया है। निशाना इन राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमशः एनटी रामाराव, चौधरी देवीलाल, प्रफुल्ल महंत और करुणानिधि, उनकी सरकारें और पार्टियां बनायी गयी हैं। यद्यपि विपक्ष की इन सरकारों को सत्ताच्युत करना कांग्रेसी अभियान का मुख्य ध्येय है, पर अभियान चलानेवाले यह भी बखूबी जानते हैं कि इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी, गफलत या भूल-चूक भारी पड़ सकती है। १९८४ में तीन सरकारों—जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम—को बर्खास्त करने के गंभीर नतीजों का उन्हें पूरा एहसास है। इन तीनों राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई थी। सिक्किम में कांग्रेस की अपनी ही सरकार थी। उसे बेदखल करने के बाद कांग्रेस लोकसभा की सभी सीटें और विधानसभा की ३२ में से ३१ सीटें हार गयी। जम्मू-कश्मीर घाटी में लोकसभा की चारों (सभी) सीटें कांग्रेस हार गयी। आंध्र प्रदेश में ४२ लोकसभा सीटों में से ३६ सीटों पर कांग्रेस पराजित हुई। विधानसभा की २९६ में से २४० सीटों पर तो तेलुगू देशम और उसकी सहयोगी पार्टियां विजयी हुई थीं। गत वर्ष जानकी रामचंद्रन की सरकार को गिराकर जिस प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसका भी कांग्रेस को भरपूर दंड मिला तथा द्रमुक (करुणानिधि) सरकार का गठन हुआ। जाहिर है, कांग्रेस-इ इस परिदृश्य को दोहराना कदापि नहीं चाहेगी।

किंतु विपक्षी सरकारें बर्खास्त करने के अपने लाभ भी हैं। सर्वप्रथम इससे विपक्ष की मात्र सत्ता ही नहीं, उसके समस्त महत्वपूर्ण संसाधन—सरकारी मशीनरी, धन और अन्य सुविधाएं—उसके हाथ से निकल केंद्र के हाथ में आ जाती हैं।

आंध्र में हिंसा: सत्ता रहित होने पर विपक्षी विधायकों की खरीद-फरोख्त करना, दल में बिखराव लाना और नेताओं को कटघरे में खड़ा करना भी आसान हो जाता है। विपक्षी नेता मानते हैं कि सरकारें गिराने की वर्तमान मुहिम इन्हीं लाभों को हासिल करने की नीयत से बनायी गयी है। हौसला अफजाई के लिए गतवर्ष कर्नाटक की बोम्मई सरकार का गिरना-गिराना है। यह

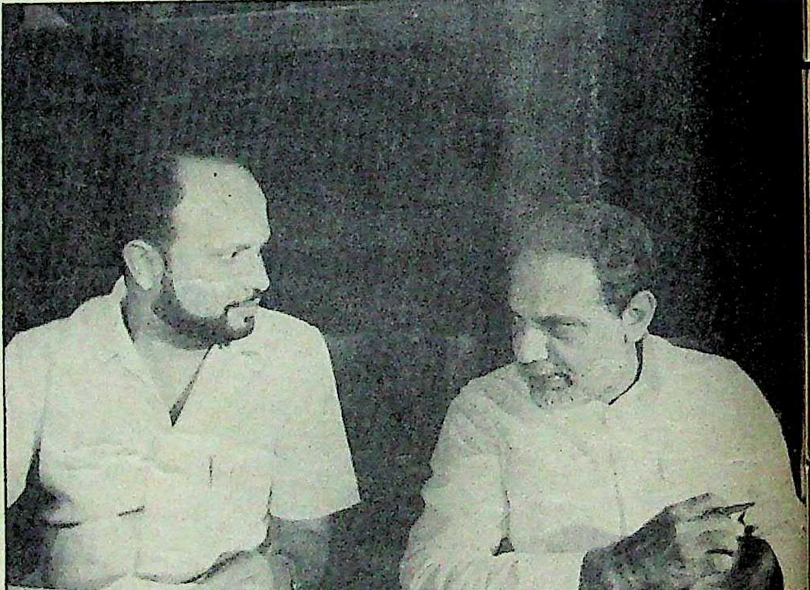

गुप्तचरी से परेशान : प्रफुल्ल महंत और रामकृष्ण हेगड़े

कांग्रेसी अभियान इतना कारगर रहा कि लाख प्रयत्नों के बावजूद विपक्ष इस 'अलोकतांत्रिक कार्यवाही' के विरुद्ध कोई व्यापक जनांदोलन तक नहीं चला सका। कारण, एक वर्ष तक चली कांग्रेसी मुहिम ने ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें दोष केंद्र के माथे से अधिक कर्नाटक में तीन-तेरह हुए जनता दल के खाते में चला गया। 'सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे' की इसी सफल रणनीति को केंद्र और कांग्रेस विपक्ष शासित अन्य राज्यों में लागू करने के आकांक्षी हो गये हैं। भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा कहते हैं, "कांग्रेस की वर्तमान सरकार गिराओ अभियान का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि उसने इसे सरअंजाम देने के लिये हिंसा का सहारा लिया है।"

आंध्र प्रदेश में बढ़ती हिंसक नक्सलवादी गतिविधियों के लिये केंद्र को सीधे-सीधे दोषी ठहराया जा रहा है। अधिकांश हत्याओं-अपहरणों में तेलुगू देशम को कांग्रेस का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हाथ दिखायी दे रहा है। यही नहीं, नक्सली समस्या से निपटने के मार्ग में रोड़े अटकाने की चर्चा भी है। जानकार सूत्रों के अनुसार आंध्र में कांग्रेसी मुहिम की कमान दो केंद्रीय मंत्रियों-वेंगलराव और पी. शिवशंकर—तथा आंध्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चेन्ना रेड्डी के हाथों में है। राज्यपाल कुमुदबेन जोशी से तकरार पुरानी है। तेलुगू देशम महासचिव पी. उपेंद्र ने 'माया' से बातचीत में कहा, "हमने नक्सलवादियों की हिंसक कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए केंद्र के समक्ष केंद्रीय सुरक्षा बल, आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जो मांग प्रस्तुत की, उसे पूरा करने की जगह राज्य में कानून-व्यवस्था का सवाल उठा राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाने का क्या औचित्य है? विशेषकर तब जब समस्या मात्र एक राज्य आंध्र की नहीं, देशव्यापी है जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों महाराष्ट्र, मप्र और उड़ीसा की जिम्मेदारी है। समस्त संसाधनों से परिपूर्ण कांग्रेस आज तक पंजाब, बिहार, जम्मू-कश्मीर और स्वयं दिल्ली में आतंकवाद और बढ़ते अपराधों की रोकथाम नहीं कर सकी है।"

इन आरोपों की काट पेश करते हुए कांग्रेस-इ के मुखर नेता कहते हैं कि केंद्र-राज्य के बनते-बिगड़ते रिश्तों और बढ़ते जन-असंतोष के लिए आंध्र सरकार व स्वयं मुख्यमंत्री कुछ कम जिम्मेदार नहीं। नक्सलवादियों को एक समय 'साथी' और 'देशभक्त' की उपाधि देनेवाले रामाराव का बदला मौजूदा कड़ा रुख उनके अंतर्विरोध का ही परिचायक है। नक्सलवादियों

का स्मारक बनाने के मुद्दे पर भी उनका रुख समय-समय पर बदलता रहा है। मुख्यमंत्री के पुत्र-दामाद-प्रेम और कुनबापरस्ती ने आग में घी का काम किया है। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद के शब्दों में, "फिल्म के माध्यम से गरीबों की सहानुभूति अर्जित कर वोट बटोरनेवाले चर्चा के अनुसार न सिर्फ प्रतिनिधिमंडल के शीर्ष

बलि देने की योजना: फारूख

दाल नहीं गलेगी: मुख्यमंत्री ज्योति बसु

रामाराव पुनः फिल्म बनाने में जुट कर मुख्यमंत्री के अपने दायित्वों से किनाराकशी कर रहे हैं। ठोस कार्यक्रमों के अभाव में जैसे-जैसे वे जनसमर्थन खोते जा रहे हैं वैसे-वैसे केंद्र का हौवा खड़ा कर रहे हैं।"

असम पर दबाव: सुदूर राज्य असम में तो चाल इससे भी अधिक गहरी है। बोडो समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने अपनी मध्यस्थता में दिल्ली में वार्ता संपन्न करा सुलह-समझौते का माहौल पैदा कर वाहवाही लूटने का प्रयास तो किया, किंतु प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से इस विषवृक्ष को समय-समय सींचा भी है। हाल की वार्ता के दौरान भी आंदोलन का नेतृत्व करनेवाले उपेंद्रनाथ ब्रम्हा की न सिर्फ विशेष आवभगत ही की गयी वरन प्रधानमंत्री से गुप्त वार्ता भी करायी गयी। सत्ता के गलियारों की नेता गुप्तचर विभाग के अतिथिगृह में ठहरे ही बल्कि वार्ता पूर्व उनकी 'ब्रीफिंग' भी इसी विभाग द्वारा की गयी। नतीजतन यदि आंदोलन में केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्रीय मंत्रियों की सक्रिय भूमिका का आरोप खुद मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत खुलेआम लगा रहे हैं, तो आश्चर्य नहीं।

'माया' को एक जानकार सूत्र से यह खास जानकारी मिली कि १९८७ में बोफोर्स विवाद के उभरने के तुरंत पश्चात एकजुट होते विपक्ष से असम और शासकदल असम गण परिषद को अलग-थलग रखने की कोशिश हुई थी। मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत को यह समझाया-बुझाया गया था कि केंद्र और असम सरकार में परस्पर सहयोग-समर्थन होना चाहिये। दलील थी कि यदि असम सरकार केंद्र को भरपूर समर्थन देगी, तो केंद्र असम सरकार को सुख-चैन की बंशी बजाने का पूरा प्रबंध करेगा। उक्त सूत्र के अनुसार महंत यह पट्टी पढ़ भी गये थे। किंतु यह केंद्र-राज्य प्रेमलीला राज्य के उभरते नेता वर्तमान केंद्रीय गृह राज्यमंत्री संतोषमोहन देव को रास न आयी। कारण, इससे राज्य और केंद्र दोनों जगह उनका अपना वजन घट जाता। अतः उन्होंने गुप्तचर एजेंसियों के सहारे गोरखालैंड के नक्शेकदम पर बोडोलैंड आंदोलन को हवा दे दी। स्वयं 'रा' के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर असम संबंधी 'आपरेशन झुमझुम' और उसके खर्च के लिए निर्धारित ३ करोड़ रु० का हवाला भी दिया है।

मौन की रणनीति: करुणानिधि

गृहमंत्री बूटा सिंह इससे सहमत नहीं। उनके अनुसार, "असम गण परिषद वाले शायद भूल गये हैं कि यह आंदोलन स्वयं उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी प्लेंस ट्राइबल्स कौंसिल (पीटीसी) के साथ शुरू किया था और उसकी मदद से विधान सभा चुनाव भी जीत लिया था। किंतु कुछ नीतियों पर अमल के मसले पर दोनों में मतभेद हो गया। युवाओं-छात्रों के 'पीटीसी' से जुड़ने से यह खाई और बढ़ी। अंततः आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बनी और यह आंदोलन उभरा।"

पर्यवेक्षकों के अनुसार असम जैसे छोटे राज्य पर केंद्रीय आक्रमण वहां की सरकार गिराने से अधिक उसे केंद्र से सुलह-समझौते के लिए विवश करने की मंशा से प्रेरित है। कारण, केंद्र को इस मुहिम में मिली सफलता विपक्ष के लिए एक जोरदार झटका साबित होगी।

हरियाणा को सबक: वैसे देखा जाये, तो एक अर्थ में रक्षाकवच की सर्वाधिक आवश्यकता इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को है। कारण, न सिर्फ उनका छोटा-सा राज्य चारों ओर से कांग्रेसी राज्यों से घिरा हुआ है बल्कि ऐन दिल्ली की नाक के नीचे है। यही नहीं, 'विपक्षी एकजुटता के लिए भरपूर भूमिका निभानेवाले देवीलाल को भरपूर सबक' सिखाने की कांग्रेसी योजना भी है। खतरा भीतरघात और पार्टी (जनता दल)—परिवार के मध्य जारी गुटबंदी और गृहयुद्ध से भी है।

कांग्रेस में देवीलाल विरोधी मुहिम की कमान भजनलाल, बंसीलाल और प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद के हाथों में बतायी जाती है। कांग्रेसी, देवीलाल के इस आरोप को कि केंद्र उनकी सरकार गिराने पर आमादा है, बेबुनियाद करार देते हैं। गुलाब नबी आजद कहते हैं, "चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। देवीलाल ने 'भेड़िया आया भेड़िया आया' कहकर जो हल्ला मचाया है, उसका मकसद अपनी अक्षमता-कुव्यवस्था पर पर्दा डालना है।" इसमें गाडगिल जोड़ते हैं, "देवीलाल अपने दो बेटों को तो संभाल नहीं सकते, राज्य क्या संभालेंगे?"

देवीलाल के दो बेटों-ओमप्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह—के बीच छिड़े उत्तराधिकार संबंधी युद्ध का ही सर्वाधिक लाभ उठाने को कांग्रेस प्रयासरत है। कुछ समय पूर्व यह अफवाह फैली थी कि बड़े भाई चौटाला के बढ़ते प्रभाव से रुष्ट रंजीत सिंह को ३५ विधायकों सहित कांग्रेस में लाने की जारी मुहिम सफलता के निकट है। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि छोटे पुत्र की बगावत की आशंका ने ही देवीलाल को गत १६ अगस्त को चौटाला की ताजपोशी करने से रोका।

हरियाणा में कांग्रेस की तख्तापलट मुहिम के दो और पहलू हैं, थैलियों का मुंह खोलना और रेलियों की भरमार करना। दिलचस्प तथ्य है कि ये दोनों स्वयं देवीलाल की राजनीतिक शैली के अभिन्न अंग हैं जिन्हें अपना कर कांग्रेस ने मियां की जूती मियां के सर पर दे मारी है। इसी रणनीति के तहत राजधानी के सम्राट होटल में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त का निष्फल प्रयास हुआ था। यह दीगर बात है कि इस प्रकरण में दोनों खेमे एक दूसरे पर दोषारोपण कर खलनायक डीगराम से अपना-अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रचंड बहुमत प्राप्त देवीलाल के किले में सेंधमारी करना आसान नहीं, इस तथ्य को कांग्रेस भलीभांति जानती है। साथ ही वह इस हरियाणवी राजनीतिक चरित्र से भी परिचित है जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने सदलबल दल-बदल लिया था। 'आयाराम-गयाराम' प्रथा की शुरुआत का श्रेय भी हरियाणा को ही है। चूंकि मेहनत का फल मीठा होता है, सो कांग्रेस सरकार हटाओ मुहिम को घाटे का सौदा नहीं समझ रही। देवीलाल और हरियाणा

साक्षात्कार/देवीलाल

सरकार गिराने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी

माया : आप यह आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं कि केंद्र गैरइंका राज्य सरकारों को गिराने की साजिश रच रहा है?

देवीलाल : यह साजिश कांग्रेस ने हरियाणा समेत सभी विपक्ष शासित राज्यों में रची है। एनटी रामाराव के खिलाफ नक्सलवादियों का मुद्दा उठाया हुआ है। असम में बोडो आंदोलन को हवा दी हैं। खुश ज्योति बसु से भी नहीं हैं। यही हालत करुणानिधि की भी है। लेकिन इनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि विपक्षी सरकारें जनमत से बनी हैं। न तो यहां के मुख्यमंत्री ऊपर से नामजद किये गये हैं और न ही आये दिन बदले गये हैं, जैसा कि कांग्रेस शासित राज्यों में होता रहा है। ज्योति बसु आज दस वर्ष से अधिक समय से मुख्यमंत्री हैं और वह भी तीन चुनाव जीत कर। एनटी रामाराव ने दो बार चुनाव मैदान में जीत हासिल कर अपने जनसमर्थन की ताकत का नमूना पेश किया है। इसी प्रकार करुणानिधि कांग्रेस और अन्ना द्रमुक दोनों को पछाड़ कर दस वर्ष बाद फिर मुख्यमंत्री बने हैं। असम में प्रफुल्ल महंत ने लंबे संघर्ष और व्यापक जनमत के बाद चुनाव जीता था और आज तक मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए चेन्ना रेड्डी जैसे को कितना भी आगे क्यों न किया जाये, दस्तखत मुहिम क्यों न चलायी जाये, विधायकों की खरीद-फरोख्त की कितनी भी तिकड़म क्यों न की जाये, हिंसक ताकतों को कितना भी बढ़ावा क्यों न दिया जाये विपक्ष की सरकारों को गिरा नहीं सकेंगे।

माया : किंतु कांग्रेस का कहना है कि किसी भी विपक्षी सरकार को गिराने की उसकी नीयत नहीं है। उसके अनुसार सरकार गिराने का शोर विपक्षी मुख्यमंत्रियों—खासकर देवीलाल—की अपनी इच्छा का प्रतीक है।

देवीलाल : यदि उनकी नीयत सरकार गिराने की नहीं, तो फिर डीगराम धारीवाल जैसे लोगों को क्यों इस काम के लिए मुकर्रर किया गया था। मेरे खिलाफ जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह भारत बंद के मुद्दे पर एक ओर पंजाब के राज्यपाल रे और दूसरी ओर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पत्रों द्वारा संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश की, जिस प्रकार के पत्र उग्रवादियों के नाम से आ रहे हैं, यह सब क्या इनकी बदनीयती का सबूत नहीं? उग्रवादी हाथ से खत लिखते हैं। किंतु मेरे पास फोटोस्टेट पत्र आये हैं, जिनकी हजारों कापियां बांटी गयी हैं। इनकी सबसे बड़ी बदनीयती और पक्षपात का सबूत एसवाईएल नहर है, जिसका वायदा इंदिरा गांधी भी कर चुकी थीं। किंतु उसे आज तक इसलिए पूरा नहीं किया

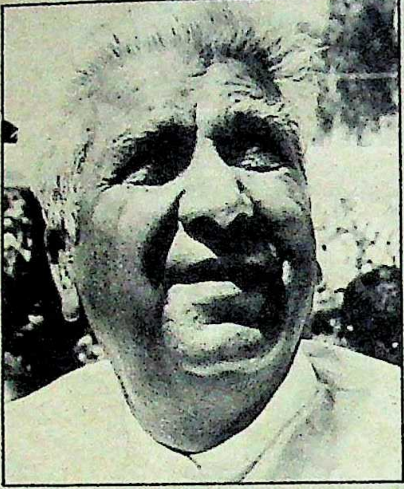

गया है कि कहीं देवीलाल को इसका श्रेय न मिल जाये। इनकी योजना ऐसी रुकावटें डालने की हैं, जिससे लोग नाराज हों, विधायक खिलाफ हो जायें और उनकी सरकार गिराने की साजिश कामयाब हो जाये।

माया : सरकार गिराने के प्रति आप मात्र सशंकित हैं अथवा इसके कुछ ठोस सबूत भी हैं?

देवीलाल : मैं पिछले दिनों जब बंगलौर में था, तो मुझे इत्तिला मिली कि कांग्रेस हमारे कुछ विधायकों को उकसाने-बहकाने और खरीदने के कदम उठा रही है। मैंने फौरन राज्य में संबंधित व्यक्तियों को चौकन्ना कर दिया। कुछ ही दिनों में सम्राट होटल (दिल्ली) प्रकरण में बात सामने आ गयी।

माया : किंतु कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद के अनुसार कांग्रेस द्वारा डीगराम को भेजना तो दूर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते भी नहीं। उनका यह भी आरोप है कि नाटकबाजी में सिद्धहस्त हरियाणा सरकार ने खुद एक आदमी खड़ा किया है, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए।

देवीलाल : जो खुद गुलाम है, वह किस मुंह से आधिकारिक बात करता है? यह तो भारत का दुर्भाग्य है कि जहां पहले मौलाना आजाद थे; वहीं अब गुलाम नबी आजाद हैं। जहां सरदार पटेल जैसे गृहमंत्री थे, वहां सरदार बूटा सिंह विराजमान हैं। जहां विट्ठल भाई पटेल जैसे लोकसभा अध्यक्ष थे, वहां बलराम जाखड़ जैसे आ गये हैं। जहां लाजपतराय जैसे लोग थे, वहां कल्पनाथ राय आ गये हैं। इन गुलामों की बात का न मैं यकीन करता हूं न दुनिया।

माया : आपके पास क्या प्रमाण हैं कि धारी कांग्रेस के ही आदमी हैं?

देवीलाल : मैं तो इस आदमी को जानता नहीं। वह एक अपराधी व्यक्ति है। उसके खि चार सौ बीसी के केस चल रहे हैं। इस साजि तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आशीर्वाद था। इसके रचने वालों में केंद्रीय खान-इस्पात माखनलाल फोतेदार, गृहमंत्री बूटा सिंह, कृषि मंत्री भजनलाल शामिल थे।

माया : कांग्रेस का आरोप है कि देवीलाल सर गिराने का सारा होहल्ला जनता का ध्यान ह के लिए है। कारण आगामी चुनाव में उतर लिए आपके पास न कोई मूल मुद्दा है न उपल

देवीलाल : हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं, जि जनता का ध्यान हटाने की सोचें। रही उपलब्धि की बात वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षित बेरोज नौजवानों को भत्ता, साक्षात्कार में जाने के निःशुल्क बस यात्रा, कर्जमाफी आदि सुवि हमने ही मुहैया करायी है। यही नहीं न्यू वेतन की रकम राज्य में बढ़ाकर ८०० रुपए कर दी हैं, जबकि राजस्थान में यह ३६४ बिहार में ४६५ रुपए, पंजाब में ६०२ रुपए, ५०० रुपए और प० बंगाल में ५६७ रुपए है। मैंने राज्य संभाला, तो यह मात्र ५०० रुपए थी बार बढ़ाने के बाद आज ८०० रुपए पर पहुंच गया है। हमारी प्रति व्यक्ति सालाना आज ४ हजार ७६५ रुपए है। हमारे राज्य में घंटे बिजली-पानी का प्रबंध है। हमें तो समस्या ही नहीं, जिससे जनता का ध्यान ह उलटे हम तो समूचे देश का ध्यान हरियाणा ओर दिलाना चाहते हैं कि वह हमारी लाइन चले, तो वैसी ही खुशहाली आ सकती है। लिए जनता से एक वोट और एक नोट की गुजारिश कर रहे हैं।

माया : विपक्ष और जनता दल में आपकी हैसियत-अहमियत का क्या कारण है?

देवीलाल : यह तो आप लोग बेहतर जानते सकते हैं। मैं तो १९२८ से जनजागरण में रहा हूं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी आजादी मिलने पर मैंने कांग्रेस के पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। बाहर आकर जनता के मुद्दों पर मैं लगातार करता रहा हूं। शायद इसी लिए लोग मु विश्वास कर मेरे साथ चलते हैं।

माया : किंतु क्या इसका प्रमुख कारण यह नहीं आप उस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली को तीन तरफ से घेर रखा है और उस धावा बोलने के धन-साधन से लैस है?

लाल: *मैं इससे इनकार नहीं करता। कुरसी र साधन के लिए ही तो सारी लड़ाई है। अगर रे पास कुरसी न होती, तो मेरे पास यह हवाई ज भी न होता, जिसकी वजह से मैं सुबह यदि लौर होता हूं, तो शाम को पटना। कभी जयपुर ी मद्रास। जहां तक जनता का प्रश्न है, वह तो २८ से मेरे साथ रही है। पद के सहारे ही मैं वी अधिक जनकल्याणकारी योजनाएं लतापूर्वक लागू कर सका हूं।*

या: किंतु आलोचकों का मानना है कि कप्रियता हासिल करने, बढ़ाने के लिए आप धन अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं।

ीलाल: *धन से मुझे कभी लगाव नहीं रहा। धन रे पास सदैव रहा है। उसे लगाकर मैंने इज्जत यी है। भजनलाल जैसों की तरह मैं कोई ओढ़नी ने वाला या बस कडक्टर नहीं था, जिन्होंने धन ाकर इज्जत गंवायी है। एक वोट एक नोट के त मुझे जो धन लोग देते हैं, उसे मैं लोगों में ही ता हूं। इस समय भी जो चार-चार, पांच-पांच ख रुपए मैं पूर्व सांसदों को सम्मान स्वरूप दे रहा वे लोगों द्वारा ही इकट्ठा किये और दिये गये ए हैं।*

या: लोग यह धन स्वेच्छा से देते हैं या जबरन ली होती है?

ीलाल: *जबरन वसूली का क्या सवाल जब लोग र आकर मुझे दे जाते हैं। हर शुक्रवार चंडीगढ़ में री प्रेस कांफ्रेंस होती है, यह लोगों को पता है। ग थैले ले चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। मैं कभी ता नहीं। मैंने तो अपने मंत्रियों को किसी ीपति के घर चाय तक न पीने की हिदायत दी है। मेरे पास दो सालों में मुख्यमंत्री राहत कोष ों पूंजीपतियों द्वारा दिये साढ़े आठ करोड़ रुपए ा हुए हैं, जिनसे मैं मैचिंग ग्रांट देता हूं। यह ीलाल को नहीं मुख्यमंत्री को मिले हैं। फर्क ना है कि मैं रुपए चेक से लेता हूं। उनका काला नहीं। भजनलाल के सात साल के अरसे में ६० ख इकट्ठा हुआ। बंसीलाल जो दो साल रहे, तो के राहत कोष में एक लाख ४२ हजार ही गया। हिर है कि वे थैलियां बटोरकर घर ले जाते थे।*

या: पिछले दो साल से चलाये गये राजीव ाओ अभियान की सफलता की कैसी संभावना ायी दे रही है?

ीलाल: *देर चुनाव होने की है। चुनाव के बाद ीव सरकार किसी हालत नहीं बन सकेगी। ली सरकार विपक्ष की होगी।*

या: बावजूद इसके कि आपका अपना जनता आज भी आपसी सिरफुटौवल में अधिक त है?

लाल: *क्या आपने इलाहाबाद का संगम देखा हां गंगा, जमुना सरस्वती का मेल होता है? कुछ दूर तक अलग दिखायी देने वाली धाराएं जाकर बिलकुल एक हो जाती हैं। जनता दल पांच पार्टियों का संगम है। नतीजतन अलग-अलग धाराएं दिख रही हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बीतेगा, सब एक होती जायेंगी।*

माया: इस बात की क्या गारंटी कि सत्ता पाने के बाद भी आप सब एक रहेंगे?

देवीलाल: *विपक्षी एकता की सबसे बड़ी मिसाल लोकसभा के सामूहिक इस्तीफे रहे। जब हम राज गंवाने (सांसदों द्वारा पदत्याग) के लिये एक हो सकते हैं, तो राज पाने और बनाये रखने के लिए क्यों नहीं इकट्ठा रहेंगे? हमने सफल भारत बंद भी यही दिखाने के लिए किया कि राजीव गांधी के खिलाफ सभी पार्टियां और जनता एक है। नतीजतन राजीव गांधी और उनकी पार्टी में हताशा-निराशा है। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।*

माया: बोफोर्स के मुद्दे पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरजी के हाल के बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

देवीलाल: *जनरल सुंदरजी के बयानों से स्पष्ट है कि राजीव गांधी भ्रष्ट हैं।*

> यदि उनकी नीयत सरकार गिराने की नहीं, तो फिर डीगराम धारीवाल जैसे लोगों को क्यों इस काम के लिए मुकर्रर किया गया था। मेरे खिलाफ जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह भारत बंद के मुद्दे पर एक ओर पंजाब के राज्यपाल रे और दूसरी ओर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पत्रों द्वारा संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश की, जिस प्रकार के पत्र उग्रवादियों के नाम से आ रहे हैं, यह सब क्या इनकी बदनीयती का सबूत नहीं?

माया: किंतु सरकार के अनुसार न सिर्फ जनरल सुंदरजी ने झूठ ही बोला है, बल्कि पूर्व सेनाध्यक्ष होने के नाते अपने दायित्व का निर्वाह भी नहीं किया है।

देवीलाल: *ऐसी पार्टी और सरकार का क्या कहना, जिसकी एक प्रधानमंत्री (श्रीमती गांधी) ने पहले हाईकोर्ट का फैसला न मान देश की न्यायपालिका का मान घटाया, जिसके मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा नियुक्त ठक्कर आयोग के निष्कर्षों को ताला-ए-ताक रखकर उस व्यक्ति को उच्च पद दिया, जिसकी ओर संदेह की सुई घूमी थी। जिसने सर्वोच्च सरकारी लेखा अधिकारी (सीएजी) की रिपोर्ट को न सिर्फ नकारा ही, बल्कि उसके विरुद्ध निन्दा अभियान चलाया। अब यही पूर्व सेनाध्यक्ष के मामले में कर रहे हैं।*

—**रंजना**

सरकार पर लगातार दबाव बनाये रखने की योजना के अंतर्गत ही ३० अगस्त के 'बंद' के दौरान रेल, सड़क मार्ग अवरुद्ध करने के मुद्दे को पंजाब के राज्यपाल एसएस रे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा विरोध पत्र भिजवाये गये। इसी कड़ी में 'भारत बंद' पूर्व होडल में रेल पटरियों पर धरना देने के देवीलाल के आह्वान पर गृहमंत्री बूटा सिंह ने संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उठा एक और संकट खड़ा किया।

कांग्रेस की मौजूदा मुहिम और हरियाणा सरकार की सांसत के लिए देवीलाल खुद कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। बात-बात पर अपने मंत्रियों के इस्तीफे लेने, सुबह बर्खास्त मंत्री की शाम को बहाली करने, गैर विधायक को मंत्री बनाने और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठानेवाले रघु यादव जैसे विधायक को दल से निकाल बाहर करनेवाले देवीलाल स्वयं अस्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक हैं, ऐसा पर्यवेक्षकों का मानना है।

करुणानिधि की शैली: इससे भी अधिक दिलचस्प प्रकरण तमिलनाडु का है। हाल में ही सत्तारूढ़ हुई करुणानिधि सरकार को गिराने से अधिक उस पर मनौवैज्ञानिक दबाव डाल अपने पुराने साथी-सहयोगी द्रमुक को अपनी ओर करने की केंद्र की मंशा पर्यवेक्षक अधिक देख रहे हैं। इस रणनीति से दोहरा लाभ है। एक, ऐसा होने पर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ होगी। दूसरे, विपक्ष से द्रमुक को अलग-थलग करने से विपक्षी हौसले काफी हद तक पस्त होंगे।

तमिलनाडु सरकार गिराने के प्रयास की बात सर्वप्रथम तब उभरी जब कांग्रेस ने हाल में जयललिता के साथ हाथ मिलाने की बात चलायी। सूत्रों का दावा है कि जयललिता ने शर्त रखी कि लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराये जायें और राज की बागडोर उनके हाथ सौंपी जाये। कांग्रेस की मौजूदा रणनीति जयललिता से खुले गठबंधन के अलावा द्रमुक से गुपचुप समझौते की है। कदाचित इसी के तहत बोफोर्स संबंधी पूर्व सेनाध्यक्ष के० सुंदरजी के रहस्योद्‌घाटन के मुद्दे पर राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष रामाराव सहित संपूर्ण विपक्ष ने राजीव गांधी से इस्तीफे की जो मांग की, उसका समर्थन करुणानिधि ने नहीं किया।

यह बदला रुख केंद्रीय वाणिज्यमंत्री दिनेश सिंह और तमिलनाडु के राजस्वमंत्री एनके मनोहरन के बीच संपन्न हाल की बातचीत का परिणाम है या ३० अगस्त के 'भारत बंद' के पूर्व फैली उस अफवाह का नतीजा, जिसके तहत 'बंद' के दौरान हिंसक वारदातें करवा केंद्र द्वारा करुणानिधि सरकार को कानून व्यवस्था भंग होने के मुद्दे पर बर्खास्त करने की योजना थी, यह कहना कठिन है। कारण, करुणानिधि ने 'बंद' में विपक्ष का पूर्ण सहयोग किया यह दीगर बात है कि 'बंद'

की पूर्व संध्या तक उन्होंने होंठ पूर्णतया सिले रखने में ही खैर समझी।

सुरेंद्र मोहन का अनुमान है कि इस तरह की चुप्पी करुणानिधि के कदाचित एक सुविचारित रणनीति के तहत केंद्र को आश्वस्त या गुमराह करने के इरादे से अपनायी थी। कारण, करुणानिधि बंद को सफल बनाने में किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री से पीछे नहीं रहे। वे अकेले मुख्यमंत्री थे जो उस दिन अपने कार्यालय भी नहीं गये। बंद की सफलता का आलम यह था कि उस दिन मद्रास के दोनों रेलवे स्टेशनों से एक भी रेलगाड़ी नहीं चली।

सुरेंद्र मोहन कुछ भी कहें, किंतु करुणानिधि की राजनीतिक शैली से परिचित अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि तमिल फिल्मों का यह लोकप्रिय पटकथाकार दोनों दरवाजे खुले रखने में सिद्धहस्त है। राष्ट्रीय मोर्चे के सम्मानित सदस्य होने के बावजूद आगामी चुनावों में यदि उन्हें विपक्षी विजय के आसार नजर न आये, तो वे अंतिम क्षणों में भी पाला बदल सकते हैं। कारण, वे न तो दस वर्षों के बनवास के पश्चात मिला सत्ता-सुख खोना चाहेंगे और न ही अपना मार्ग कंटकपूर्ण बनायेंगे।

केंद्र की ताकत: दिनोंदिन बढ़ते सत्ता के केंद्रीकरण के चलते केंद्र के पास राज्य सरकारों के मार्ग में कांटे बोने की अपार शक्ति हो गयी है। समय-समय पर इसका जायज-नाजायज उपयोग कर हर केंद्र सरकार ने राजनीतिक लाभ उठाया है। निर्णय का आधार मूलतः यह है कि केंद्र किस राज्य सरकार से कितना अधिक खुश या नाखुश है और किसके लिए कितनी समस्यायें खड़ी करना चाहता है। मसलन पश्चिम बंगाल और केरल की वामपंथी सरकारों को अभी केंद्र की सीधी चांदमारी से अलग रखा गया है। मुख्य कारण एक तो यह है कि इनके गढ़ अपेक्षाकृत अधिक मजबूत है और दूसरा यह कि केंद्र और कांग्रेस को अभी भी वामपंथियों को बहला-फुसला कर अपने पक्ष में करने की उम्मीद है। किंतु सांकेतिक डंडा बरसाने के लिए तमिलनाडु के साथ-साथ इन सरकारों के भी चावल कोटे में भारी कटौती की गयी है। रणनीति यही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अव्यवस्थित हो जाये, जनअसंतोष उभरे और राज्य सरकारें अलोकप्रिय हो जनाधार खो बैठें।

हरियाणा को सांसत में डालने के लिए कुछ भिन्न हथकंडे अपनाये गये। जनता दल राज्य अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला कहते हैं, "हर मोड़ पर केंद्र ने हमारे विकास कार्यों में आर्थिक संकट पैदा किये हैं। भयंकर सूखा पड़ा, तो मात्र २० करोड़ और बाढ़ की विभीषिका में मात्र ३० करोड़ रु० दिये। इसके विपरीत नागालैंड जैसे छोटे राज्य को भी हमसे तिगुनी-चौगुनी राहत रकम मुहैया की गयी। एक ओर हरियाणा में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। दूसरी ओर उससे निपटने के मार्ग में पर्याप्त साधन मुहैया न करके उलटे रोड़े अटकाये गये।

साक्षात्कार: एआर मल्लू, **महासचिव, असम कांग्रेस कमेटी**

गैरइंका सरकारें जनाधार खो चुकी हैं

माया: ***क्या कांग्रेस विपक्षी सरकारें गिराने की मुहिम चला रही है?***

एआर मल्लू: *हम भला क्यों सरकार गिरायेंगे? वह भी ऐन चुनाव पूर्व? सरकारें गिराना न हमारी संस्कृति है न परंपरा। हमारा जनता के हाथ की सत्ता में विश्वास है, धन और बल की सत्ता में नहीं।*

माया: ***फिर ऐसी आशंका असम, हरियाणा व आंध्र आदि के मुख्यमंत्री बारंबार क्यों व्यक्त कर रहे हैं?***

मल्लू: *अपने किये-अनकिये पर परदा डालने के लिए वे ऐसी गलतबयानी कर रहे हैं। अधिकांश विपक्षी सरकारें क्षेत्रीयतावाद, संप्रदायवाद, भाषावाद के आधार पर व झूठे सब्जबाग दिखा सत्तारूढ़ हुई हैं। मसलन आंध्र में तेलुगू गौरव को उभारा गया, असम में क्षेत्रीयतावाद के तहत, 'असम असमियों का' जैसा नारा दिया गया, तो हरियाणा में कर्जमाफी जैसे लुभावने नारे बुलंद हुए। कार्यक्रमविहीन ऐसी सरकारों की ढोल की पोल नजर आने में देर नहीं लगती। नतीजतन जैसे-जैसे इनका जनाधार खिसकने लगता है, वैसे-वैसे वे अपनी खामियों को केंद्र के मत्थे मढ़ने लगती हैं। यदि असम और आंध्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-पर दिन बदतर होती जा रही है, तो इसके लिए केंद्र को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?*

—रंजना

बहरहाल, केंद्र की मौजूदा रणनीति विपक्ष शासित सरकारों को गिराने की नहीं, तो उसकी नीवें हिला देने की अवश्य है। एक कांग्रेसी सांसद ने बताया कि सरकारें गिराने से हम उन्हें अधिक लाभान्वित करेंगे। अतः उनको अधिक से अधिक अलोकप्रिय बनाना हितकर होगा जिससे या तो वे चुनावपूर्व स्वयं गिर जायें या चुनाव हार जायें। मुख्यमंत्रियों-विशेषकर देवीलाल और रामाराव का चरित्र-हनन इसी रणनीति का एक जरूरी हिस्सा है। राज्य में निरंतर एक न एक संकट-बवंडर खड़ा कर इन मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्य में कैद और राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार अभियान से वंचित रखना, इसकी अगली कड़ी है। दल-बदल से, चाहे वह इक्का-दुक्का ही क्यों न हो, कार्यकर्ता और मतदाता के मन में संशय उभारने का प्रयास जारी है। यही नहीं, दल-बदल, अंतर्कलह, चरित्रहनन आदि से साख गिरा कर धन-स्रोत सुखाने की भी संभावना बढ़ी है। उद्योग जगत के एक जानकार सूत्र ने 'माया' को बताया कि पक्ष और विपक्ष को औद्योगिक घराने क्रमशः ७० और ३० प्रतिशत धन मुहैया कर रहे हैं। नजदीक आते चुनाव में ऊंचे-नीचे होते पलड़े के साथ इस समीकरण में भी फेरबदल अवश्यंभावी है। कांग्रेसी रणनीति विपक्ष को कमजोर दिखा उसके चुनाव कोष को रिक्त करने की है।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अहम प्रश्न यह है कि क्या इन प्रयासों से विपक्षी सरकारें गिरेंगी? 'माया' को प्राप्त जानकारी के अनुसार बढ़ती हिंसक घटनाओं के बहाने जम्मू-कश्मीर सरकार गिराने की योजना लगभग तैयार है। इससे कांग्रेस दोहरा लाभ उठाना चाहेगी। एक तो पाकिस्तान से लगे इस संवेदनशील राज्य की सरकार गिरने का व्यापक विरोध नहीं होगा। दूसरे, इस साझा सरकार, जिसमें स्वयं कांग्रेस भी शामिल है, को गिराने से यह फिजा पैदा करने में आसानी होगी कि केंद्र किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। वैसे भी कांग्रेस पार्टी किसी भी विपक्षी सरकार को गिराने में कभी भी सिद्धांतों और लोकतांत्रिक परंपराओं को ताख में रखने में कोताही नहीं बरतती।

अन्य विपक्षी सरकारें-आंध्र, हरियाणा और तमिलनाडु गिरेंगी या गिरायी जायेंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र को कौन, कब और किस प्रकार का सुअवसर प्रदान करता है। केंद्र-राज्य की इस रस्साकशी के चलते यदि चरित्र-हनन के नये अध्याय खुलें, घोटालों का पर्दाफाश हो, हरियाणा में आगामी कुछ सप्ताहों में आतंकवाद की एक-दो बड़ी घटनाएं घटें, आंध्र और असम में हिंसक घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो, तो आश्चर्य नहीं।

—रंजना कक्कड़

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

छाया: गिरीश

सूखी और गीली सड़कों पर भी मज़बूत पकड़. पानी के बेहतर खिंचाव के लिए ज़्यादा साइप. ज़्यादा मज़बूत पकड़ और आरामदेय सवारी के लिए ट्रैड ब्लॉक. लगातार बने हुए खांचे ताकि टायर गरम न हो. मोड़ों पर अधिकतम पकड़ के लिए ट्रैडेड शोल्डर्स. अधिक चपटे ट्रैड ताकि टायर कहीं कम, कहीं ज़्यादा न घिसे. संपूर्ण संतुलन के लिए समान रूप से बने साइड ट्रैड. गहरे खांचे ताकि हवा घुस कर धूल-कचरा बाहर निकाल दे. ये ख़ूबियां हैं **टी वी एस श्रीचक्रा टायरों** की जिनमें **आपकी ज़्यादा सुरक्षा** के लिए लॉक-इन ट्रैड है.

TMF 8651
TSH66
'LOCK-IN' TREAD
FOR ADDED SAFETY
सुरक्षा ऐसी कि आप पूरा भरोसा कर सकें.
श्रीकांत तो करते हैं.
TVS
SRICHAKRA
TYRES

R K SWAMY/STL/7258/HIN

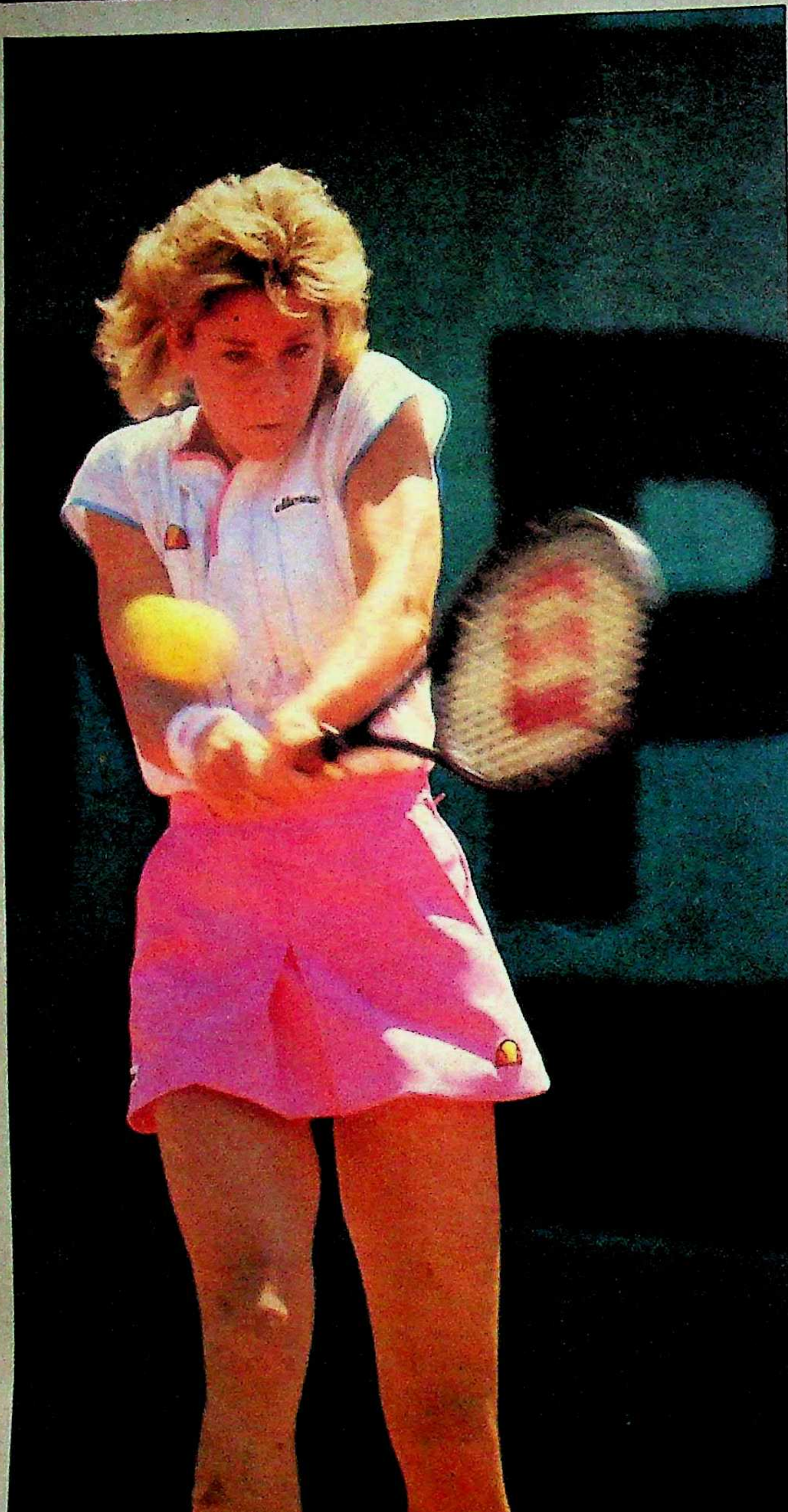

क्रिस एवर्ट का संन्यास

अलविदा एवर्ट

८ सितम्बर, १९७१ को एक १६ वर्षीय बालिका क्रिस एवर्ट ने अमरीकी ओप टेनिस प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में प्रवे पाकर तहलका मचा दिया था। तब से इस महा महिला टेनिस खिलाड़ी ने निरंतर पिछले १८ व में सफलता की नयी सीमाएं तय की हैं। परंतु सितंबर, १९८९ को ३४ वर्षीय इसी खिलाड़ी अपना इस प्रतियोगिता में अंतिम मैच खेला। य एक महिला टेनिस युग की समाप्ति का सूचक था।

एवर्ट के टेनिस जीवन ने पिछले दो दशकों में काफी उतार-चढ़ाव भी देखा है। और-तो-और खेल भी परिवर्तन के कई पड़ावों से गुजरा है। परंतु इस नामी महिला खिलाड़ी की सफलता-यात्रा ने निरंतर नयी मंजिलें तय कीं, जिसमें उसने खू नाम व दाम कमाया। ये सफलताएं किसी भी युव टेनिस खिलाड़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती हैं।

उनके टेनिस जीवन का लेखाजोखा करने पता चलता है कि कुल मिलाकर एवर्ट १,३० मैचों में सफलता की भागीदार बनीं, जिनमें १५ एकल प्रतियोगिताओं में वे चैंपियन रहीं। जबकि १४६ मैचों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा।

अमरीकी आयकर विभाग के अनुसार उन्होंने अपने टेनिस जीवन में ८,८५८,१९ डालर की धनराशि कमायी, जिसमें ६७४,५९८ डालर उन्होंने अमरीकी ओप प्रतियोगिता से अर्जित किये हैं।

नाम व दाम के ये आंकड़े संभवतः एव की महानता को सिद्ध नहीं करते। ६ सितंबर को जब अमरीकी अश्वेत महिला खिला जीना गैरिस ने क्रिस एवर्ट को अमरीकी ओपन क्वार्टर फाइन में पराजित किया, तो फ्लशिंग मीडोस का दृ अवर्णनीय लगा। विजेता गैरिसन की आंखों

आंसुओं ने पराजित एवर्ट की महानता को सिद्ध कर दिया।

इस बहुचर्चित विजय के बारे में गैरिसन के उद्गार बहुत ही भावुक रहे। "जीत के बाद जब मैं जाकर बैठी, तो मैंने अपने आपसे पूछा कि अभी-अभी भला हुआ क्या है? हम लोग अंतिम बार एवर्ट को कोर्ट पर देख रहे हैं। मेरा मन भर आया। और मैं तो खलनायिका कहलाऊंगी, जिसने इस महान महिला को हरा दिया...परंतु लोग इस प्रकार तो मुझे अवश्य याद करेंगे..." अपनी अश्रुधारा को रोकते हुए, वे बोलीं, "जी हां। ये आंसू इसलिए हैं, क्योंकि मुझे वह जमाना याद आ रहा है, जब मैं १५ वर्ष की थी। मैं ह्यूस्टन में एवर्ट को खेलते हुए देखने जाया करती थी और उनके 'आटोग्राफ' प्राप्त करके गद्गद हो जाती थी...ये आंसू इसलिए हैं, क्योंकि उनकी इस खेल में अपनी एक मान्यता है..."

पहली जीत: अमरीकी ओपन के अपने अंतिम मैच में २ सितंबर को एवर्ट ने इस प्रतियोगिता में अपना १००वां मैच जीतकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। अपनी यहां की पहली जीत के बारे में एवर्ट का कथन है: "मेरी पहली जीत यहां काफी आसान थी। मैंने पश्चिम जर्मनी की नामी खिलाड़ी ईड्डा बडिंग को सन १९७१ में पहले चक्र में हराया था। उस समय मुझे वरीयता क्रम में स्थान के लिए उचित व योग्य नहीं समझा गया था। परंतु फिर भी सेमी फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही और अंत में चैंपियन बिली जीन किंग ने मेरे विजयी अभियान को धराशायी कर दिया था।"

फोर्ट लौडरडेल, फ्लोरिडा की निवासी एवर्ट को जब इस वर्ष ७ जुलाई को पश्चिम जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने विंबलडन सेमी फाइनल में पराजित किया, तो लगा कि महिला टेनिस इतिहास ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। क्योंकि जिस समय (१९७४ में) एवर्ट ने पहला विंबलडन खिताब जीता था, तो ग्राफ केवल पांच वर्ष की नन्ही बालिका थी।

कुछ ही दिन बाद जब ग्राफ ने मार्तिना नवरातिलोवा को विंबलडन फाइनल में पराजित कर दिया, तो संकेत साफ था कि एवर्ट और नवरातिलोवा बीते दिनों की टेनिस सम्राज्ञियों के दिन लद गये हैं।

एवर्ट जब १९७१ में पहली बार अमरीकी ओपन के सेमी फाइनल में पहुंची, तो वे सबसे युवा खिलाड़ी थीं जो उतनी दूर तक पहुंच पायी थीं। इसी प्रकार १९७२ में वे अपने पदार्पण पर ही विंबलडन प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में पहुंचने वाली भी सबसे कम आयु की खिलाड़ी की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल हुईं।

अगले दो वर्षों में वे महिला टेनिस की चोटी पर पहुंचने में सफल हुईं। उन्हें २३ में से १६ प्रतियोगिताओं में चैंपियन बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। वे १०७ में १०० मैच जीतकर अपने टेनिस कौशल का प्रदर्शन करके खेल प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मार्च से सितंबर १९७४ तक सात महीनों में वे दस लगातार प्रतियोगिताओं में अपना डंका बजवाने में सफल रहीं।

अपने टेनिस काल में एवर्ट १८ में से १७ वर्षों में विंबलडन सेमी फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुईं। यही नहीं, विंबलडन सम्राज्ञी की उपाधि से उन्हें १९७४, १९७६ और १९८१ में सुशोभित भी किया गया।

उनके टेनिस जीवन का अवलोकन करने से पता चलता है कि उन्होंने फ्रांसीसी ओपन चैंपियनशिप १९७४, १९७५, १९७९, १९८०, १९८३, १९८५ और १९८६ में जीती। जबकि विंबलडन सफलता की सिरमौर वे १९७४, १९७८ व १९८१ में बनीं। उधर अमरीकी ओपन में उनका बोलबाला १९७५, १९७६, १९७७, १९७८ व १९८० में रहा। आस्ट्रेलियाई ओपन ने उनके टेनिस कारनामों का चमत्कार १९८२ और १९८४ में जमकर देखा। इन्हीं सफलताओं के आधार पर ही विशेषज्ञों और समीक्षकों ने उन्हें वरीयता क्रम में १९७५ से १९७८ तक अव्वल नम्बर पर रखा था।

व्यक्तिगत जीवन: एवर्ट के व्यक्तिगत जीवन ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले उनकी मंगनी जिमी कानर्स से हुई जो टूट गयी। उधर १९७९ में जब उन्होंने ब्रिटिश डेविस खिलाड़ी एंडी मिल से विवाह कर लिया, तो लगा कि वैवाहिक जीवन का सुख उनके खेल को निखारने में सहायक होगा। परंतु यह विवाह बंधन शीघ्र लड़खड़ाने लगा और १९८७ में उनका तलाक हो गया। इन विषम परिस्थितियों ने उन्हें सौम्य बना दिया।

एवर्ट की महिला टेनिस को कई देनों को भुलाया नहीं जा सकता है। खिलाड़ियों के फैशन को नयी दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका प्रमुख रही है। विंबलडन पोशाकों के निर्माता टेड टिंगलिंग का कहना है कि 'लेस से लैस' स्कर्ट फैशन प्रचलित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

एक जमाना था जब आस्ट्रेलिया की मार्ग्रेट कोर्ट और अमरीका की बिली जीन किंग महिला टेनिस पर छाई हुई थीं। परंतु एवर्ट ने खेल को अलग ही दिशा प्रदान की। वे बराबर 'बेस लाइन' पर अपने दो हत्थे 'बैक हैंड' द्वारा प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का इंतजार करती थीं। बस फिर क्या था, चार साल के अंतर में ही कोर्ट ने टेनिस से संन्यास ले लिया और एवर्ट अपनी टेनिस शक्ति किंग से आजमाने लगी थीं। उन्होंने दिखा दिया कि बिन बात 'नेट' पर भागने में कुछ नहीं रखा है। पीछे 'बेस लाइन' पर रहकर खेल गति संतुलित कर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर सकते हैं। यह एक नया मंत्र था खिलाड़ियों की सफलता के लिए।

१९७९ में इटालवी ओपन प्रतियोगिता के सेमी फाइनल तक एवर्ट को ट्रेसी आस्टिन नामक बालिका ने जब पछाड़ दिया था, तो उसे आभास नहीं हुआ था कि उसकी यह जीत सदैव उल्लेखनीय रहेगी। क्योंकि तब तक एवर्ट 'क्ले कोर्ट' पर लगातार १२५ मैच जीत चुकी थीं। कीर्तिमानों से सुसज्जित ऐसी चोटी की खिलाड़ी को घुटने टेकने पर मजबूर करना वास्तव में अपने आप में एक महान उपलब्धि थी।

अब एवर्ट केवल कुछ नुमायशी मैचों में तो अवश्य भाग लेंगी, परंतु किसी 'ग्रांड स्लैम' प्रतियोगिता में उनके भाग लेने की संभावनाएं बहुत कम हैं। हां, फेडरेशन कप (महिलाओं का डेविस कप) में मार्तिना नवरातिलोवा के साथ वे अमरीका का प्रतिनिधित्व अवश्य करेंगी।

इसे एक संयोग ही कहा जायेगा कि एवर्ट और नवरातिलोवा का टेनिस जीवन लगभग समांतर चला है। दोनों ही एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रही हैं। परंतु इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि दोनों के बीच घमासान स्पर्धा के कारण ही महिला टेनिस का स्तर नयी ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है। अब तक दोनों के बीच खेले गये मैचों का हिसाब-किताब ४३-३७ नवरातिलोवा के पक्ष में है। कोर्ट पर जहां दोनों के बीच जमकर मुकाबला होता था, वहां मैदान के बाहर दोनों में हार्दिक एवं आत्मीय मित्रता है।

हाल के अमरीकी ओपन क्वार्टर फाइनल में पराजय के पश्चात मुंह लटकाये हताश एवर्ट जब फ्लशिंग मीडोस मैदान से बाहर की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो आठ वर्षीय एक बालक ने उन्हें रोककर कहा, "ऐ क्रिस मैं सिर्फ तुम्हें शुभकामना देना चाहता हूं।" वे रुकीं, बच्चे की तरफ भावभीनी नजरों से देखा और 'थैंक यू', कहकर मैदान से बाहर और टेनिस अखाड़े से सदैव के लिए ओझल हो गयीं। संभवत: उस बालक ने अनगिनत कृतज्ञ टेनिस प्रेमियों की ओर से एवर्ट को शुभकामनाएं प्रदान की थीं।

इसमें दो राय नहीं कि एवर्ट का नाम महिला टेनिस इतिहास में तो अमर रहेगा ही, परंतु उन्होंने जो स्थान टेनिस प्रेमियों के मन में बनाया है, उसका स्थान कोई भी नहीं ले पायेगा। अलविदा एवर्ट।

—रवि चतुर्वेदी

पैंतालीस पत्नियों के पति की शामत

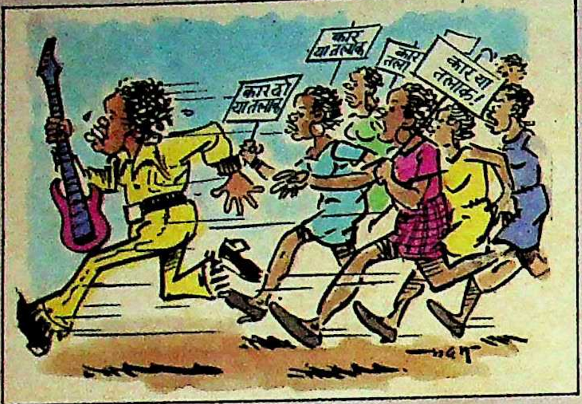

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ४५ पत्नियों का पति है और १५ कन्याओं का मंगेतर? आप कल्पना कर पायें या न कर पायें, पर यह हकीकत है कि अफ्रीका का एक पाप स्टार ऐसा ही व्यक्ति है। नाम है—ओबामा। लेकिन बेचारा ओबामा अब संकट में फंस गया है। संकट यह है कि उसकी ४५ पत्नियों में से १५ पत्नियों ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उनको पति से तलाक चाहिए। जानते है कारण क्या दिया है? कारण यह है कि उनका पति उनको एक कार खरीद कर नहीं दे पा रहा है। ओबामा बेचारा इसलिए परेशान है कि ऐसी कोई कार नहीं खरीद पा रहा, जिसमें उसकी पंद्रहों पत्नियां एक साथ बैठ सकें। वह कार के बदले एक मिनी बस लेना चाहता है तथा उसके लिए उसने बात भी शुरू कर दी है। जो भी हो, १५ पत्नियों द्वारा दायर किया गया तलाक का यह मुकदमा फिलहाल कोर्ट में है और ओबामा को उम्मीद है कि कोर्ट कोई-न-कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे उसे समुचित न्याय मिल सकेगा।

मक्खीमार

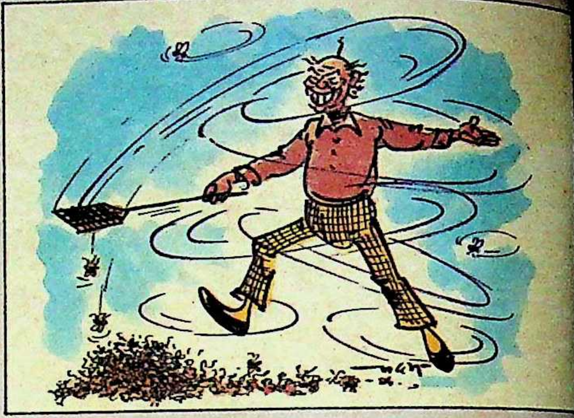

यों तो 'मक्खी मारना' एक मुहावरा है, लेकिन कोई इस मुहावरे को अपनी निजी जिंदगी में चरितार्थ करे और सचमुच मक्खियां मारने का शौक पाल ले, तो उसे आप क्या कहेंगे? आप कुछ भी कहें, पूर्वी बीजिंग का निवासी हू-चा-ग्फू अवकाश प्राप्त करने के बाद से सचमुच मक्खियां मार रहा है। जिनहुआ न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि १९७९ से अब तक हू १७.५ किलोग्राम मक्खियां मा
चुका है। गर्मियों में वह ४०
मक्खियां—यानी लगभग १००
मक्खियां प्रतिदिन की दर से मार
रहा है। उसके इस शौक के बारे
पूछे जाने पर वह बताता है कि
चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी सेहत
रहें, इसलिए मैंने ऐसा
पाला—औंर फिर रिटायर होने
बाद मक्खियां मारने के सिवा वह
भी क्या सकता है?

लत से निजात

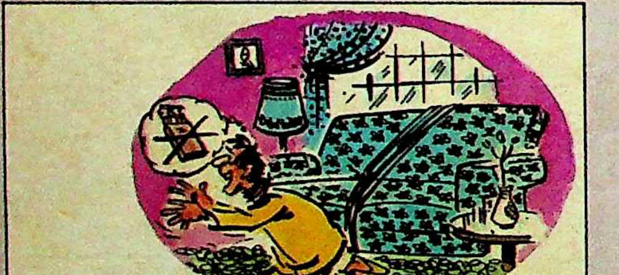

लत तो लत है, बुरी हो या अच्छी, लाख कोशिश के बाद भी नहीं छूटती, लेकिन अमरीका निवासी ४२ वर्षीय थामस वारेन ने सिगरेट पीने की अपनी बुरी आदत पर विजय पा ली है। इस इल्लत से निजात पाने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका अपनाया। उन्होंने ७.६ मीटर का एक स्टील का तार लिया और कुत्ते की तरह उसका फंदा अपने गले में डाल दिया। उसका दूसरा छोर अपने सोफे से बांध दिया। लगभग तीन सप्ताह तक वे हठयोगियों की तरह तार से बंधे रहे। जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि बिना सिगरेट के भी उनका काम चल जायेगा, तब उन्होंने अपने आपको उससे मुक्त कर लिया। अपनी इस आदत पर विजय पाने के बाद उन्होंने खुशी में अपने दोस्तों को दावत भी दी।

जो बढ़े सो पाये

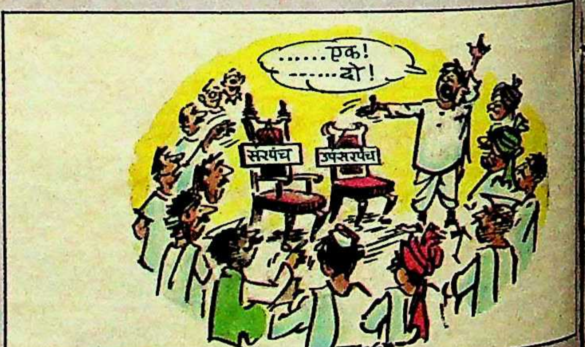

चुनाव कोई भी हो बिना पैसे, बिना गुंडई या बिना गुट्टीबाजी के जीतना आजकल जरा मुश्किल है। इसलिए पिछले दिनों ग्राम पंचायत के चुनाव में सतारा जिले के खंडाला तालुका के गांव मोर्वे के निवासियों और पंचायती समिति ने सोचा कि चुनाव कराना झंझट का काम तो है ही, पानी की तरह बेजा पैसा भी बहता है, सो सरपंच और उपसरपंच के पदों की क्यों न नीलामी ही कर दी जाये। बस आनन-फानन गांव के मंदिर पर ही सभा जुट गयी
बोली लगनी शुरू हो गयी।
की अधिकतम बोली १३५००
तक गयी, जिसे लगाया सदा
जगताप ने तथा उपसरपंच
अधिकतम बोली ५५०० रुपए
पहुंची, जिसे लगानेवाले थे शिव
धियागुडे। इस नीलामी के बाद
हुआ कि इस धन को गांव के वि
में लगाया जाये।

—संयोजन: डा० मुस्ताक

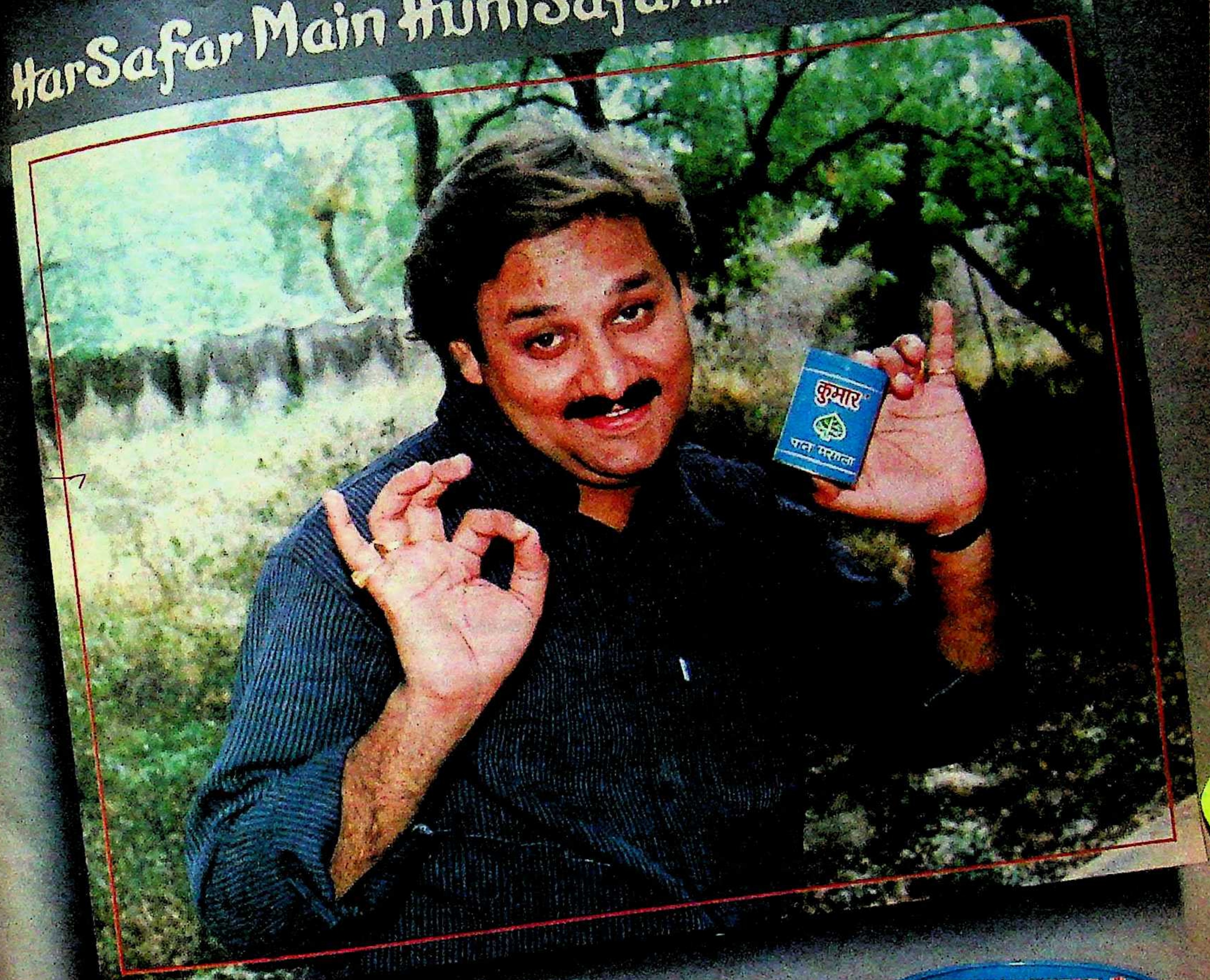
Har Safar Main Hum Safar....
कुमार
पान मसाला

KUMAR®
PAN MASALA
कुमार®
पान मसाला
कुमार
पान मसाला
ज़र्दा मिक्स

KUMAR®
PAN MASALA

Mfd. by— **Kumar Chemicals, Kanpur-208 001**
PHONE No. : 52303, 52305

Statutory Warning : Chewing tobacco is injurious to health

NOTE : DEALERSHIP ENQUIRIES SOLICITED FOR UNREPRESENTED AREAS.

eGangotri

इसके ताने में, इसके बाने में, इसकी बुनावट में...

भारत. प्राचीन, सच्चा, तराशा हुआ. अनगिनत रचनात्मक धाराओं का स्रोत.
आज तक उल्लास से भरा हुआ. और कहाँ मिलेगा इसका सबसे अधिक, आकर्षक
और सबसे ज़्यादा विभिन्न रंगो में सजा इसका रूप, हाथ से बुने वस्त्रों का जादू सा भंडार? भारत के
हैंडलूम! उज्ज्वल, जटिल, अभिरचित, राष्ट्र संबंधी, प्रभावशाली, लुभावने...
भारतीय हैंडलूम में बसी है भारत की आत्मा.

हैंडलूम हाउस का पूर्ण
नैशनल डिज़ाईन कलेक्शन अब स्पेशल सबसिडाईज़्ड मूल्यों पर
पूरे वर्ष के लिए.

...बसी है भारत की शान!

handloom
house

Sarees ○ Dress Materials ○ Readymades ○ Furnishings ○ Carpets ○ Bed, Bath & Table Linen

THE ORIGINAL ONE STOP SHOP

Ahmedabad • Bangalore • Baroda • Bombay • Calcutta • Chandigarh • Coimbatore • Delhi • Ernakulam • Gorakhpur • Hyderabad • Imphal • Jaipur
Madras • Madurai • Patna • Ranchi • Secunderabad • Surat • Vijayawada • Vishakapatnam

Interact:AIH:176 A1 Hin

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक २०
३१ अक्तूबर, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टाल्स्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१७०९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५, लखनऊ कार्यालय: बी-१०१ [illegible] अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७, पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५९७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९१०३५, जयपुर कार्यालय: ए-२०, शांति पथ, तिलकनगर, जयपुर-४, फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित

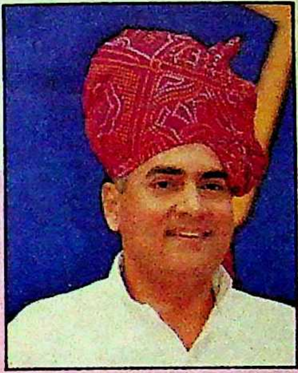

२६
आवरण कथा

आगामी चुनाव में कांग्रेस की नैया को किनारे लगाने में सर्वाधिक भूमिका कांग्रेस-इ के सात मुख्यमंत्रियों को निभानी है। ये हैं: नारायण दत्त तिवारी, सत्येंद्र नारायण सिंह, मोतीलाल वोरा, शरद पवार, अमर सिंह चौधरी, शिवचरण माथुर और जेबी पटनायक। क्या ये मुख्यमंत्री इतने सक्षम और स्थिर हैं कि कांग्रेस का सफल चुनाव-संचालन कर सकें? सर्वाधिक निर्णायक प्रांत उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सक्षम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की निष्ठा पर उंगली क्यों उठायी गयी? क्या संदेहों से घिरे मुख्यमंत्रियों के बलबूते कांग्रेस चुनाव-विजय का सपना देख सकती है?

देवीलाल
देवीलाल के ७५वें जन्म-दिन पर दिल्ली में हुई विशाल सभा क्या देवीलाल का निजी शक्ति-प्रदर्शन था? २२

वामपंथ बनाम भाजपा
वामपंथियों और भाजपा के बीच विवाद के कौन से मुद्दे अभी भी विपक्षी एकता में बाधा बने हुए हैं? ५३

जनरल सुंदरजी
पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरजी की आलोचना करके कांग्रेसी राजनेता सेना को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? ८५

अजेय सिंह
वीपी सिंह के पुत्र अजेय सिंह अपनी संपत्ति की घोषणा के बाद क्या सभी आरोपों से मुक्त हो गये? ९०

ट्रांसफर-पोस्टिंग
चहेते अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में मंत्री-विधायक सर्वाधिक रुचि क्यों ले रहे हैं? १७

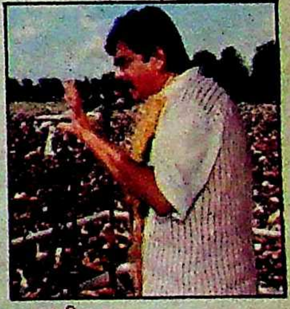

शत्रुघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार में शुरू हुआ जनजागरण अभियान क्या उनके राजनीति में आने का संकेत है? ७०

दिल्ली दरबार: भीड़ जब जनता बन जाये १०
फोटोफीचर १३
विशेष रिपोर्ट: मुख्यमंत्रियों की ट्रांसपोर्ट कंपनियां: सत्ता के पहियों पर दौड़ता धंधा ३८
व्यक्तित्व: जयदेव बघेल: चौकीदार से विश्वविख्यात कलाकार ४६
दूरदर्शन: छोटे परदे की नयी रानियां ५०
देश: पायलटों की भगदड़ ५९
राजस्थान: कोटा का दंगा क्या पूर्वनियोजित था? ६५
उत्तर प्रदेश: हल्द्वानी कांड: पुलिस बर्बरता की नयी मिसाल ७४
दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक आंदोलन ७७
बेढब ९३
परदे के पीछे ९६

क्या नए ओनिडा पर प्रतिबंध लगाया जाए?

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ से.मि. एफ.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे का टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली ख़ूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?

ओनिडा २१

पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

माया
नौजवान किसको वोट देंगे?

आगामी चुनाव: नौजवान किसको वोट देंगे?

'माया' का ताजा अंक मिला। आवरण कथा 'आगामी चुनाव: नौजवान किसको वोट देंगे?' बहुत पसंद आयी। आपने अपनी आवरण कथा के अंतर्गत जो सर्वे आईएमआरबी से कराया है, ज जाने उस पर कुछ-कुछ संदेह होता है। राजीव गांधी की छवि धूमिल है, उनकी ईमानदारी पर लगातार कीचड उछाले जा रहे हैं, फिर भी इस रिपोर्ट के हिसाब से राजीव गांधी को ज्यादातर लोग अच्छा मानते हैं, ईमानदार मानते हैं, कम भ्रष्ट मानते हैं। आश्चर्य तो यह है कि सीएजी की रपट के बाद भी ज्यादातर मतदाता राजीव गांधी के इस्तीफे के पक्षधर नहीं हैं। कुछ मामलों में जैसे स्थायी सरकार देने और विकास के मुद्दों पर आईएम-आरबी की रपट सही लगती है। सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी नकारात्मक बातें जाती हैं, फिर भी अधिकतर मतदाता कांग्रेस-इ को वोट देने के पक्ष में हैं। आईएमआरबी के बरक्स जो सर्वे आपकी टीम ने किया है, वह वास्तविकता के ज्यादा नजदीक लगता है। लेकिन सही हार-जीत की भविष्यवाणी करना खतरनाक है, क्योंकि भारतीय मतदाता के मन में क्या है, यह कोई नहीं जानता। **—अब्दुल रहमान, फूलबाग, कलकत्ता**

जिया की हत्या की साजिश का अब परदाफाश

'माया' का ३० सितंबर, १९८९ का अंक पढ़ा। 'माया' को इकट्ठा किये गये दुर्लभ तथ्यों के लिए धन्यवाद। [illegible] है, और नहीं है, यह जिया की मौत से साबित हो गया है। जिया ने पाकिस्तान के उत्थान तथा जनता की भलाई के लिए क्या किया, यह हम नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य है कि जिया की मौत से तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पाकिस्तान की जनता को राहत अवश्य मिली होगी। **—सीताराम चौबे, बिहार कृषि सेवा, रीगा, सीतामढ़ी, बिहार**

राजनीति में राजघरानों की वापसी का मतलब

३० सितंबर की 'माया' में प्रकाशित लेख सचाई से ओतप्रोत रहा। राजघराने बगैर आनाकानी किये अपनी संपत्ति देश के जरूरतमंदों को सौंप देंगे, यह अतिशय रूमानी आशावाद से बढ़कर कुछ नहीं। **—वेद प्रकाश त्रिपाठी, महू वाया-गंजबासौदा, विदिशा**

भारत बंद: कितना उचित?

३० सितंबर का अंक प्राप्त हुआ। विवाद 'भारत बंद' पढ़ा। बंद का आयोजन कब तक चलता रहेगा, बंद से कितना नुकसान है देश को, कभी सोचा है बड़े नेताओं ने। सफल और असफल (विफल) में कितनों के घर उजड़ते हैं, कितनों की जानें जाती हैं। क्या यह सब देशहित में है?**—शाहिद खान, गांधीवार्ड, गाडरवारा, मप्र**

कांसीराम क्या कांग्रेस का साथ देंगे?

'माया' का ३० सितंबर '८९ का अंक पढ़ा। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में कांसीराम की 'बसपा' किस तरफ झुकती है, इसका सटीक जवाब तो शायद स्वयं कांसीराम के पास भी नहीं है। हां, उनके विचारों से झूठे स्वाभिमान व अत्यधिक आत्मविश्वास की बू अवश्य आती है। उनके उत्तेजक विचारों से जहां सवर्णों के प्रति घृणात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, वहीं कांसीराम आशा से कहीं अधिक आशावान मालूम होते हैं। **—विजय प्रताप सिंह, मु/पो—वेस्टचिरमिरी, सरगुजा**

मोहन कात्रे की दिलचस्पी

कि[illegible] तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो की भी आलोचना होना कोई नयी बात नहीं है ('माया': ३० सितंबर अंक), किंतु इस समय ब्यूरो से ज्यादा विवादास्पद उसके निदेशक मोहन कात्रे हैं। इतने संवेदनशील विभाग के एक अधिकारी को कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बनाये रखने से यह शंका होनी स्वाभाविक ही है कि ये मामलों को सरकार के अनुकूल ढंग से निपटाये जाने का ईनाम है।**—बृजराज किशोर, १२९, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून**

बूंद-बूंद: घड़ा भर विवाद

३० सितंबर की 'माया' में बूंद-बूंद: घड़ाभर विवाद' पढ़कर आंखें हैरत से फैल गयीं। लगता है केके तिवारी जैसे राजीव के शुभचिंतक उनका सर्वनाश करके ही रहेंगे। क्या जरूरत थी 'बूंद-बूंद' के स्थगन की? यह एक सामान्य सीरियल की तरह गुजर जाता और लोगों को पता भी न चलता। नाहक प्रचार की वजह से फिल्म किस्सा कुरसी का जैसी लोकप्रियता इसे मुफ्त में मिल गयी। **—राजीव लोचन मंटू, ग्रा० घोसैठ, पत्रा-पीरी बाजार, जिला मुंगेर, बिहार**

डब्बाबंद समाचार

'डब्बा बंद समाचार' ('माया': ३० सितंबर) के द्वारा ममता कालिया ने 'भारत बंद' के संदर्भ में सरकारी संचार माध्यमों के पक्षपातपूर्ण रवैये का सटीक आकलन किया है।**—मनोज पटेल, सी-१०८, मेंहदौरी कालोनी, इलाहाबाद**

अनुवादक चाहिए

हमें बंगला, गुजराती और मराठी से हिंदी में अनुवाद के लिए ऐसे सुयोग्य एवं अनुभवी अंशकालिक अनुवादकों की आवश्यकता है, जिन्हें दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान हो तथा जो अपने स्थान पर हमारे यहां से प्रेषित सामग्री पर समयबद्ध कार्य कर सकें। बंगला से हिंदी अनुवाद के लिए इलाहाबाद में भी कई पूर्णकालिक और अंशकालिक स्थान रिक्त हैं। आवेदन पत्र बायोडाटा के साथ १५ दिन के अंदर प्रधान संपादक, मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, २८१, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद—३, के पते पर प्रेषित करें।

स्पष्टीकरण

दिनांक ३० सितंबर, १९८९ की 'माया' में 'खबरों के आगे, खबरों के पीछे' स्तंभ में 'हरिकेश बहादुर की परेशानी' शीर्षक एक आइटम प्रकाशित हुआ है। उसमें बहुत सी बातें तथ्यों से परे हैं। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि 'वीपी सिंह के पूर्व सचिव अशरफ ने पिछले दिनों हरिकेश बहादुर की मदद से एक जाली पत्र अमरीकी दूतावास के नाम बनवाया था।' मैं कभी भी इस प्रकार के अनर्गल कार्य नहीं करता, यह मेरी आदत भी नहीं है।**—हरिकेश बहादुर, पूर्व सांसद, कैंप, नयी दिल्ली**

सांसदों का कहना है

१५ सितंबर, १९८९ के अंक में मैंने एक बात पायी जिसको जानकर बड़ा दुख हुआ। इस पत्रिका के 'विपक्ष को बगावत की उम्मीद' के पन्ना १९ के तृतीय कालम की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। उसमें यह लिखा गया है कि ऐसे सांसद भी हैं जिन्हें लगने लगा है कि राजीव गांधी उन्हें अगला चुनाव नहीं जिता सकेंगे और अगर वे विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें, तो जीत के आसार अच्छे रहेंगे। ऐसे सांसदों में जिनके नाम दिये गये हैं, उनमें मेरा नाम भी है। संपादकजी, कौन हैं चर्चा करनेवाले या चर्चा में आने का कोई आधार भी हो सकता है। मैंने कभी किसी विरोधी नेता से न कोई बात की और न कोई बात सुनी तथा न ही किसी से कभी कानाफूसी की।**—एमपी यादव, मेम्बर आफ पार्लियामेंट (लोकसभा), २ फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली**

१५ सितंबर, १९८९ का 'माया' अंक देखा। 'विपक्ष को बगावत की उम्मीद' शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ १९ पर बेचैन एवं डंका छोड़नेवाले संभावित सांसदों में अपना नाम देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि एक निष्ठावान तथा १९४२ के आंदोलन से कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति का नाम असंतुष्टों की सूची में डालकर और कांग्रेस छोड़ने की झूठी एवं बेबुनियाद संभावना व्यक्त करके आप पत्रकारिता के किस मापदण्ड को स्थापित करना चाहते हैं।**—जगन्नाथ चौधरी, (संसद सदस्य, लोकसभा), ७ पं० पंत मार्ग, नयी दिल्ली**

कोई भी व्यक्ति—चाहे वह इस समय कितना ही विख्यात और लोकप्रिय हो—हमारा इतिहास नहीं बदल सकता। इतिहास घटनाओं और मुद्दों से बदलता है, व्यक्तियों से नहीं। **—चंद्रशेखर, इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया**

गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री का पत्र भी रोकने लगे हैं। **—राजीव गांधी**

कल को यदि प्रधानमंत्री थानेदारों को भी इसी तरह सीधे पत्र लिखे (जिस तरह सरपंचों को लिखा है), तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। **—देवीलाल, इंडियन एक्सप्रेस**

कांग्रेस-इ वामपंथी पार्टियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। **—क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, दिल्ली अधिवेशन**

कांग्रेस-इ एक राजनीतिक लाश है, अगले चुनाव तक हमें इसे कंधा देते रहना है। **—वीपी सिंह, जनसत्ता**

कांग्रेस-इ ठीक गंगा की तरह है, यह पवित्र है और कभी भी गंदी नहीं हो सकती। **—कल्पनाथ राय**

बजबजाते मेनहोल के कीड़े सार्वजनिक सभा में दावा कर रहे हैं: हम गंगा की गोद में पले हैं। **—अरुणेश नीरन (कवि), सवाक**

कांग्रेस-इ हैजा है, तो भाजपा प्लेग। दोनों में ज्यादा बुरी कौन है? **—ईएमएस नंबूदिरीपाद**

माकपा वही बात रटती है जो उसे बाहरी शक्तियां सिखाती हैं, वह भारतीयों की आकांक्षाएं समझती ही नहीं। **—भाजपा महासचिव केएल शर्मा**

मेरा मानना यह है कि अरुण नेहरू और वीपी सिंह विरोधी दलों को मिलाकर एक नकली कांग्रेस बना रहे हैं। ——**अकबर अहमद डंपी**

राजीव गांधी कात्रे का कार्यकाल बढ़ाते हैं और कात्रे राजीव गांधी का। **—वीपी सिंह**

मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अंबानी और कात्रे दोनों, व्यवहार में एक ही हैं। **—राम जेठमलानी, 'न्यूज ट्रैक'**

वे (नारायणदत्त तिवारी) सक्षम आदमी हैं, वे विकल्प बन सकते हैं, लेकिन उनमें साहस का अभाव है। अगर उनमें दम-खम आ जाये, तो शीर्ष-पद के शेष सारे गुण हैं उनमें। **—वीपी सिंह**

गद्दारी मेरे रक्त में नहीं है। मैं सदा वफादार रहा हूं और रहूंगा। **—नारायणदत्त तिवारी**

वे क्या करें? पार्टी और उसके नेतृत्व से गद्दारी नहीं कर सकते, इसलिए देश और समाज से गद्दारी करने के लिए बाध्य हैं। **—शतरुद्र प्रकाश, जद नेता**

अगर कोई मुझे पागल कहता है, तो क्या मैं दर-ब-दर यह साबित करता फिरूं कि मैं पागल नहीं हूं? **—एबीए गनी खां चौधरी**

मेरे लिए बिहार दूसरी किसी भी चीज के मुकाबले ज्यादा अहमियत रखता है। **—शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता**

चीन में लोकतंत्र हमेशा रहा है। **—बुद्धदेव भट्टाचार्य, विधायक पबं विधानसभा**

मैं तो (देश के) बंटवारे के पहले से चिल्ला रहा हूं कि उर्दू को सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम को रास आनेवाली लिपि और शब्द-भंडार दे दो, तो सारा फसाद ही खतम हो जायेगा, मगर सियासतवाले सुनते कहां हैं? **—नजीर बनारसी (शायर), स्वतंत्र भारत**

राष्ट्रीय हित और हिंदू हित अलग नहीं हो सकते। **—अटलबिहारी वाजपेयी**

मुख्यमंत्री (शिवचरण माथुर) को चाहिए कि वे जिन नौकरशाहों के प्रति अंधविश्वास पाले हुए हैं, उन्हें प्रशासन सौंपकर घर बैठें। **—इंका विधायक शिवराम शर्मा, टाइम्स आफ इंडिया**

राजनीतिक ढोंग है शहाबुद्दीन की इंसाफ पार्टी। **—जाबिर हुसैन, बिहार के पूर्व स्वास्थ्यमंत्री**

मैं, दर-असल, जनता स्कूल का स्नातक हूं। **—सैयद शहाबुद्दीन**

यह (जवाहर रोजगार योजना) कोई नयी चीज नहीं है—जवाहरलाल ने जो रोजगार इंदिरा को दिया, वही इंदिरा ने राजीव को दिया, और अब राजीव गांधी वही रोजगार राहुल (अपने बेटे) को देंगे। **—प्रमोद महाजन, भाजपा सांसद**

जनता दल में भीड़ आकृष्ट करनेवाले दो ही आदमी हैं—एक मैं और दूसरे वीपी सिंह। **—मेनका गांधी**

जनता दल में शामिल होने के बाद वे वही वीपी सिंह नहीं रह गये हैं। **—शरद जोशी**

दिल्ली में कुछ भी गोपनीय नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार सारे राज लीक करनेवाली है। **—केआर सुंदर राजन, संडे ऑब्जर्वर**

अगर एनटी रामाराव बोफोर्स तोप की क्षमता जांचना ही चाहते हैं, तो अपने दोनों राजनीतिक दामादों के साथ तोप के सामने ३० किमी दूर खड़े हो जायें और तोप को दग जाने दें। **—डा० वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र के इंका विधायक**

जमीन के एक छोटे-से टुकड़े और एक पुरानी इमारत में क्या रखा है? राम तो हमारे दिलों में रहते हैं, सारे संसार में रहते हैं। **—गृहमंत्री बूटा सिंह**

देवीलाल

मेनका गांधी

श्री (सिद्धार्थशंकर) राय पंजाब में रुकने के लिए आये हैं, भागने के लिए नहीं। **—पंजाब राजभवन का प्रवक्ता**

मैं चौधरी साहब (चरण सिंह) की विरासत को आगे बढ़ा सकता हूं। विदेश में मेरे वर्षों तक रहने का कोई अर्थ नहीं, मेरा जन्म और पालन-पोषण तो यहीं हुआ है। **—अजीत सिंह, टाइम्स आफ इंडिया**

क्या मैं प्रधानमंत्री होना चाहती हूं? मैं तो पर्यावरण मंत्री होना चाहती हूं, क्योंकि यह पद स्वयं लेकर प्रधानमंत्री पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। **—मेनका गांधी**

किसी गलती को कभी दुहराओ मत, नयी गलतियां करते जाओ। **—फिल्म निर्माता सईद मिर्जा**

भारतवासी आवश्यक रूप से भावुक होते हैं, उन्हें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें दिल की बात हो, वह उनके दिल को छू लेगी। मैं भी बंदूक के मुकाबले गुलाब का फूल ही पसंद करता हूं। **—फिल्म निर्माता यश चोपड़ा, टाइम्स आफ इंडिया**

अंग्रेजी में किसी भारतीय लेखक का विचार बहुतेरे लोगों का ध्यान ऐसे आकृष्ट करता है जैसे अपने पिछले पांवों पर खड़ा होकर डा० जान्सन का कुत्ता। **—जय दुबाशी, आर्गनाइजर**

आप प्रेसवाले असीम स्वतंत्रता चाहते हो, ताकि देश को बेच भी दो, तो कोई न रोके। **—केके तिवारी**

मेरा खयाल है कि राज्य (जम्मू-कश्मीर) में समाचारपत्र आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। **—डा० फारूक अब्दुल्ला**

जो नेता जितना ही भ्रष्ट है, उतना ही समाजघाती है, उसे उतने ही खलते है समाचारपत्र और पत्रकार। **—राजेंद्र माथुर**

मैं चीफ मिनिस्टर (मुख्यमंत्री) हूं चीप मिनिस्टर (सस्ता मंत्री) नहीं। **—देवीलाल**

इस आजादी ने गरीब को क्या दिया है? भोजन? नहीं। आवास? नहीं। वस्त्र? नहीं।...क्या हमारे नेताओं के त्याग-बलिदान का उद्देश्य यही था? **—एनटी रामाराव**

पम्प चले तो फ़सल फले
पम्प बंद तो काम मंद

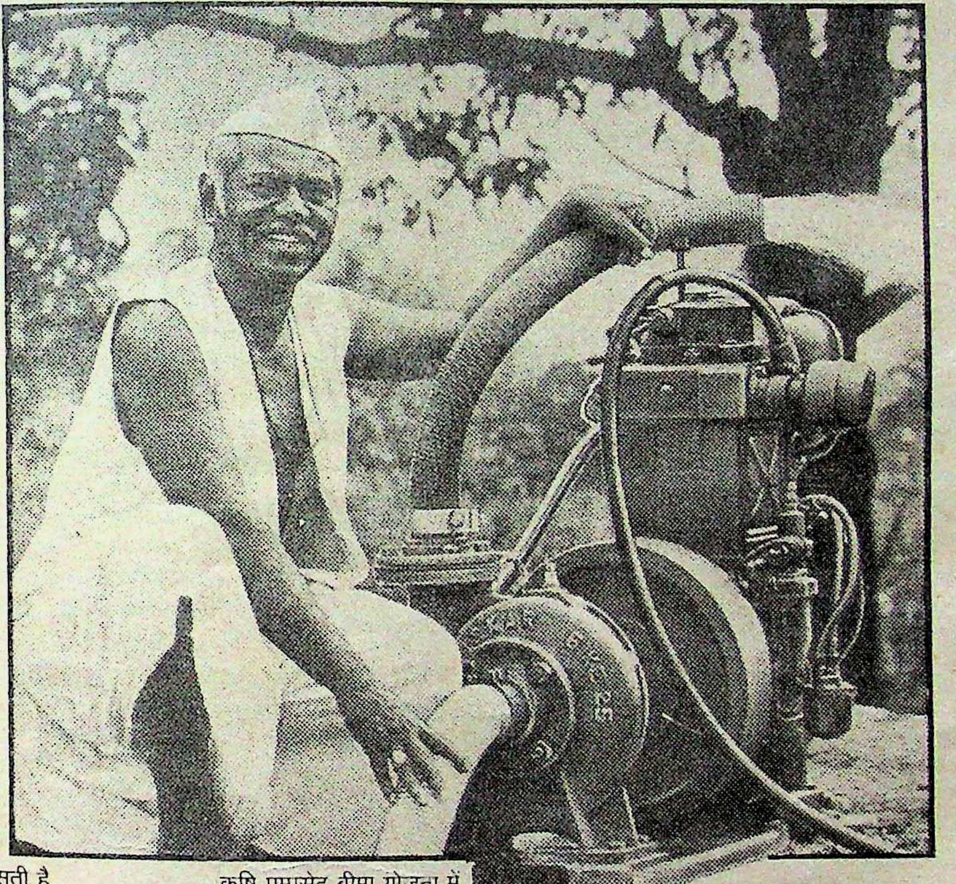

किसान की जान उसकी फ़सल में बसती है, तो फ़सल की पानी में. अच्छे बीज, अच्छी खाद और कमरतोड मेहनत सब बेकार हो जाएं अगर फ़सल को समय पर पूरा पानी न मिले.

खड़ी फ़सल को पानी की ज़रूरत हो, कुएं में पानी भी हो और ऐसे में पम्प जल जाए, टूट जाए, बिगड जाए या चोरी हो जाए तो किसान तो बरबाद हो जाए.

ऐसी मुसीबत में किसान को सहारा देता है **न्यू इन्डिया का कृषि पम्पसेट बीमा.**

कृषि पम्पसेट बीमा योजना में सबमर्सिबल पम्पसेट सहित सभी तरह के पम्पसेटों का बीमा किया जाता है.

कृषि पम्पसेट बीमे की दर : मोटर की हॉर्स पावर के हिसाब से कम से कम 50 रुपये सालाना.

न्यू इन्डिया के 1000 से भी अधिक कार्यालय देशभर में फैले हुए हैं.

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीक के कार्यालय में पधारें या एजेंट से मिलें. आपकी सेवा के लिए दूरदराज के गांवों में भी न्यू इन्डिया के ग्रामीण प्रतिनिधि तैनात हैं.

कृषि पम्पसेट बीमे के लिए

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कंपनी

हर मुसीबत में आपका सहारा

देश

१६ सितंबर : गोवा विधानसभा अध्यक्ष दयानंद नर्वेकर द्वारा एक युवती से छेड़खानी करने के आरोप में इस्तीफा। तमिलनाडु के बोदीनायकनूर क्षेत्र मे हरिजनों एवं सवर्णों के बीच संघर्ष, ६७ मरे।

१७ सितंबर : नेहरू ट्राफी हेतु मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, संगीतज्ञ नौशाद, क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर तथा सांसद सुनील दत्त का चयन।

१८ सितंबर : जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुत्र अजेय सिंह द्वारा अपनी विदेशी संपत्ति की घोषणा।

१९ सितंबर : कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव कराने के लिए रेल रोको आंदोलन के तहत भाजपा के ७०० कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह के अवसर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता प्रारंभ, विश्व के तेज धावक कार्ल लुइस की १०० मीटर दौड़ में पराजय।

२० सितंबर : कश्मीर के पूर्व पर्यटन मंत्री आरएस चिब पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण नेशनल कांफ्रेंस से निष्कासित।

२१ सितंबर : रिलायंस उद्योग समूह के महाप्रबंधक जनसंपर्क कीर्ति अंबानी और अर्जुन बाबरिया की जमानत २० अक्तूबर तक बढ़ी।

२२ सितंबर : असम के शरद चंद्र सिन्हा पुनः कांग्रेस-स के अध्यक्ष निर्वाचित। नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य शब्बीर अहमद सलारिया जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित।

२३ सितंबर : हिंदी दैनिक 'अमर उजाला' के प्रधान संपादक अनिल अग्रवाल का निधन। भारतीय शांति सेना के ६०० जवान लंका से भारत के लिए रवाना।

२४ सितंबर : जनता दल के विद्रोही विधायक रघु यादव द्वारा हरियाणा विधानसभा तथा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र।

२५ सितंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के ७५वें जन्म दिन के अवसर पर दिल्ली में एक विशाल रैली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की वामपंथी सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एबीए गनी खान चौधरी के नेतृत्व में एक लाख लोगों द्वारा रैली।

२६ सितंबर : सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार ६९ वर्षीय हेमंत कुमार मुखर्जी का निधन।

२७ सितंबर : धरती-से-धरती पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी' का श्री हरिकोटा केंद्र से सफल प्रक्षेपण। तीन विपक्षी पार्टियों—जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ५० हजार कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर भुवनेश्वर में गिरफ्तारी। हरियाणा जनता दल के विधायक रघु यादव कांग्रेस-इ में शामिल।

२८ सितंबर : स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा वेतन संबंधी मांग को लेकर दो दिन की देशव्यापी हड़ताल शुरू। गुजरात के मजिस्ट्रेट एमएनएल पटेल की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के तीस हजारी न्यायालयों के वकीलों द्वारा हड़ताल।

२९ सितंबर : व्यापक विरोध के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उर्दू बिल पारित, बिल के विरोध में बदायूं में प्रदर्शन, दो गुटों के बीच संघर्ष, २३ मरे १५० घायल।

३० सितंबर : आगामी नेहरू कप और शारजाह कप के लिए श्रीकांत भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नियुक्त।

अजेय सिंह

हेमंत कुमार

कार्ल लुइस

फर्डिनेंड इ मार्कोस

विदेश

१६ सितंबर : ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ५७ वर्षीय लार्ड ट्रेफर्ड का निधन।

१७ सितंबर : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एफडब्ल्यूडी क्लार्क द्वारा मंत्रिमंडल की घोषणा। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों द्वारा बांग्लादेश बंद का आह्वान।

१८ सितंबर : सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के राजा बने। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त एल मेहरोत्रा और श्रीलंका के विदेश सचिव बीपी तिलक रत्ने के मध्य नये समझौते के तहत शांति सेना को ३१ दिसंबर '८९ तक भारत वापस बुलाने पर सहमति।

१९ सितंबर : पाकिस्तानी सीनेट द्वारा सियाचिन क्षेत्र से भारतीय फौजों को तत्काल हटाये जाने की मांग। अंगोला अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक का १५२वां सदस्य बना।

२० सितंबर : मक्का में जुलाई '८९ में हज के दौरान बम विस्फोट कांड में गिरफ्तार २० अभियुक्तों में से १६ को मृत्यु दंड तथा ४ को आजीवन कारावास।

२१ सितंबर : सोवियत संघ की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के तीन सदस्यों की छुट्टी, राष्ट्रपति गोर्बाचेव के दो समर्थक व्लादीमीर क्रिश्कोव और यूरी मालस्यूकोव पोलितब्यूरो में शामिल।

२२ सितंबर : कंबोडिया से वियतनाम के सैनिकों की वापसी प्रारंभ। नोबुल पुरस्कार देनेवाली संस्था स्वीडिश अकादमी के तीन सदस्यों द्वारा सलमान रुश्दी के मामले पर अकादमी के रुख से क्षुब्ध होकर इस्तीफा।

२३ सितंबर : अश्वेत राष्ट्रीय नेता नेल्सन मंडेला की मेरी बेंसन द्वारा लिखित जीवनी 'नेल्सन मंडेला' पर से दक्षिण अफ्रीका में तीन साल पुराना प्रतिबंध समाप्त।

२४ सितंबर : मलेशिया में होनेवाली राष्ट्रमंडल की बैठक में मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को आमंत्रण। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तथा पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के बीच तनाव बरकरार।

२५ सितंबर : अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा अगले दस सालों में सारे रासायनिक हथियार नष्ट कर देने की घोषणा।

२६ सितंबर : कंबोडिया से वियतनामी सैनिकों की पूर्ण वापसी। चीन में हत्या एवं लूटपाट के अपराध में १५ व्यक्तियों को फांसी। सोवियत संघ रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए अमरीका से सहमत। श्रीलंका के उत्तर पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री वरदराजा पेरुमल शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए फिर से चुनाव कराने के लिए तैयार।

२७ सितंबर : श्रीलंका में युद्ध विराम के पहले दिन ३५ सिंहली उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण।

२८ सितंबर : फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति ७२ वर्षीय फर्डिनेंड इ मार्कोस का दिल का दौरा पड़ने से निधन। चीनी सरकार द्वारा फिलिस्तीनियों को पूर्ण समर्थन का ऐलान।

२९ सितंबर : आस्ट्रेलिया के मशहूर गिटारवादक जान विलियम्स भारत के १९८८ के उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार से सम्मानित। शिकागो निवासी मशहूर पत्रकार ८१ वर्षीय जान ब्राइट का निधन।

३० सितंबर : अंतरराष्ट्रीय नौकायन संघ के अध्यक्ष थोमस केलर का हृदय गति रुक जाने से निधन।

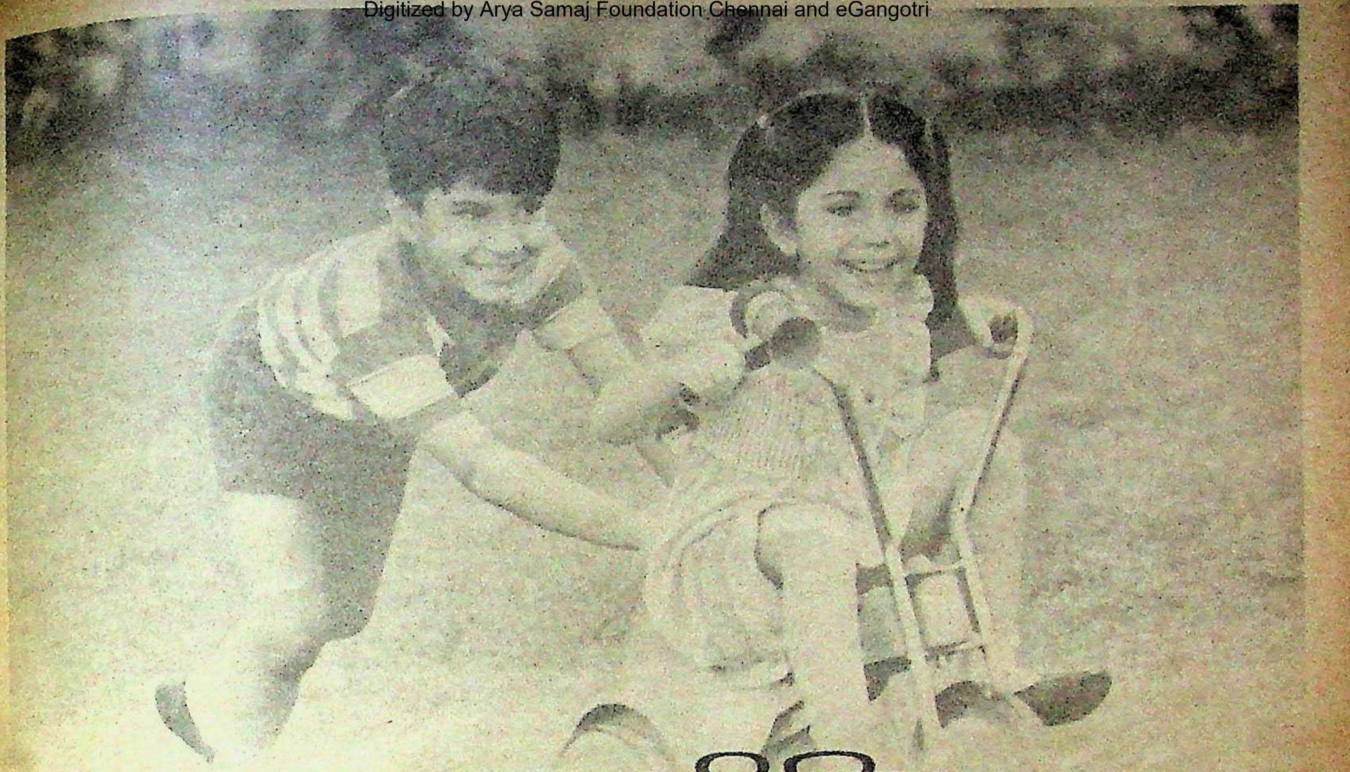

कल्पना कीजिए, ये दस साल बाद कैसे होंगे !

आपके प्यारे-दुलारे बच्चे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर होंगे, जिन्हें देख आपको गर्व होगा। मां होने के नाते आप उनका जीवन बनाने के लिए सब कुछ जो कर रही हैं।

और आपकी प्यार-भरी देखभाल में उन्हें उचित पौष्टिकता देना भी शामिल है।

हॉर्लिक्स की पौष्टिकता। आपके बढ़ते बच्चों के लिए।

"हॉर्लिक्स में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज पदार्थ—होते हैं।

और साथ में, मजबूत दांतों और स्वस्थ हड्डियों के लिए अधिक कैल्शियम भी।

यही है हॉर्लिक्स की पौष्टिकता जिससे आपका बढ़ता बच्चा चुस्त और तन्दुरुस्त रहता है।"

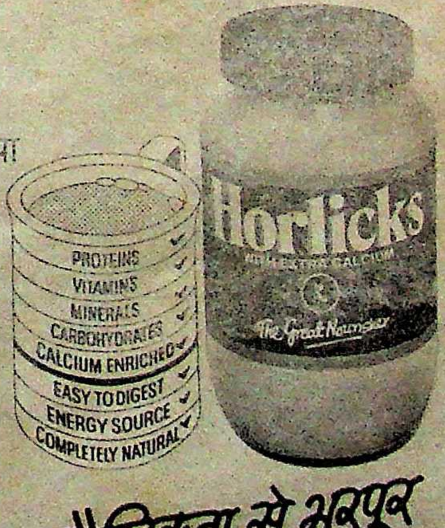
PROTEINS
VITAMINS
MINERALS
CARBOHYDRATES
CALCIUM ENRICHED
EASY TO DIGEST
ENERGY SOURCE
COMPLETELY NATURAL
Horlicks
The Great Nourisher

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6223 HIN

भीड़ जब जनता बन जाये

२५ सितंबर को जब चौ० देवीलाल साठे (साठ) पर पाठा (पंद्रह) मार कर दिल्ली के बोट क्लब पर अपने ७५वें जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, तो इंका के २४ अकबर रोड पर चुनावी अंक गणित के सवाल हल किये जा रहे थे। मल्लू पश्चिम बंगाल के चुनावी सवाल पर 'मल्लयुद्ध' कर रहे थे, पीछे से उनके ऊपर गनी खां चौधरी अपनी स्टेनगन ताने खड़े हुए थे, "मल्लू, अपने सवाल में से प्रियो (प्रियरंजन दास मुंशी) को निकाल दो। तुम्हारे सवाल का जवाब निकल आयेगा।" मन-ही-मन पहाड़े बुदबुदाते हुए मल्लू ने पीछे घूमकर देखा, "दादा, प्रियो को निकाल देंगे तो सवाल ही अधूरा हो जायेगा। आप थोड़ी देर चुप तो रहें, मैं पहाड़ा भूल जाता हूं।" मल्लू फिर से मन-ही-मन पहाड़ा बुदबुदाने लगे, तो विट्ठल गाडगिल और केएन सिंह मन-ही-मन अपने पहाड़े बुदबुदाते हुए आ गये। गाडगिल ने कहा, "यह दिल्ली दरबार हम लोगों से बेकार कसरत करवा रहा है। उसके कंप्यूटर ने चुनावी गणित के सारे सवाल पहले ही हल कर लिये हैं।" मल्लू ने पहाड़े बुदबुदाते हुए गाडगिल की तरफ देखा, लेकिन कुछ न बोलकर पहाड़े बुदबुदाना जारी रखा। केएन सिंह ने बुदबुदाना छोड़कर बोलना शुरू कर दिया, "विट्ठल भाई। इंका मुख्यालय में हम खाली बैठे बनिया (महामंत्री) क्या करें? तराजू पर अपने-अपने बट्टे ही तौलें।" मल्लू ने भी बुदबुदाना बंद कर दिया, "केएन, इतना कड़वा सच क्यों बोलते हो। लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। भइन, तुम तो डूबोगे, हम लोगों को भी अपने साथ ले लोगे।" विट्ठल गाडगिल ने खैनी-तंबाकू पर चूने की रगड़ाई अंगूठे से मारी और होंठों में दबाते हुए बोले, "सुल्तानपुरिये ठाकुर, मल्लू भाई ठीक कह रहे हैं। अगर कड़वा सच बोलने का इतना ही शौक है, तो राजा मांडा (वीपी सिंह) की शरण में क्यों नहीं चले जाते हो?" केएन सिंह ने त्यौरी चढ़ाते हुए गाडगिल के कंधे पर हाथ रख दिया, "भाई साहब, आपने मुझे समझा नहीं है। मेरे सिर पर लाल टोपी रूसी है। अरे हमने रजवाड़े ठाकुरों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, तो फिर मेरी कार्ल मार्क्स की लाल किताबों का क्या होगा! चाहे वह पेप्सी कोला हो या कोको कोला, मेरे लिए तो कड़वा सच बोलना...।" केएन अपना वाक्य पूरा ही कर रहे थे कि शीला कौल अपने कक्ष से चिल्लाती हुई निकलीं, "अरे विट्ठल कहां हो? हाट लाइन पर दिल्ली दरबार से जार्ज चिल्ला कर कह रहा है कि देवीलाल की बोट क्लब रैली में तीन लाख लोग जमा हो गये हैं। दरबार का आदेश है कि सारे काम बंद करके रैली के विफल होने वाले बयान तुरंत जारी किये जायें।" थरथर कांपती शीला कौल को विट्ठल गाडगिल ने पकड़ते हुए कहा, "मैं यहां हूं बुआजी, आप इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? आप आराम से कुरसी पर बैठ जायें! देवीलाल की रैली पर बयान जारी करने का जिम्मा भजनलालजी का है। वह बयान जारी कर देंगे।" शीला कौल कुरसी पर बैठते-बैठते फिर से खड़ी होकर चिल्ला पड़ीं, "नहीं, नहीं, जार्ज का कहना है कि पानी सिर से ऊपर है। भजनलाल के बूते में नहीं है कि देवीलाल की इस लाखों की रैली को हजारों की रैली में बयान देकर बदल पायें। इंका मुख्यालय से बयान जारी किया जाना है कि देवीलाल की रैली बिलकुल विफल हो गयी।" विट्ठल गाडगिल ने शीला कौल को फिर से कुरसी पर बिठाकर ठंडे पानी का जग थमा दिया, "बुआजी, आप उत्तेजित न हों। अपने इंका मुख्यालय में हर मौके का बढ़िया-से-बढ़िया रेडीमेड बयान बना पड़ा है। बस तारीख बदली और बयान जारी हुआ। इसमें परेशान होने की इतनी क्या जरूरत है?" शीला कौल ने ठंडे पानी का जग अपने मुंह में लगाये-लगाये गाडगिल साहब की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाकर कहा, "अच्छा, अपने इंका मुख्यालय में हर तरह का रेडीमेड बयान पड़ा हुआ है। वैरीगुड!" इतने में विट्ठल ने होंठ में दबे तंबाकू को थूका और ताजा चूने से बनी खैनी तंबाकू की दूसरी चुटकी होंठों में दबा ली और बयान ढूंढ़ने के लिए अपने कक्ष में चले गये।

बोट क्लब की भीड़ को देखकर कृषि भवन की छत पर चढ़े भजनलाल परेशान हो उठे थे। उनका दिल कर रहा था कि वे छत से छलांग लगा लें। लेकिन हिम्मत न जुटा पाने पर वे झल्ला उठे, "वर्मा (निजी सचिव) मुझे नीचे उतरने का रास्ता दिखाओ।" वर्मा ने भजनलाल को नीचे उतरने का सीढ़ियों का संकरा-सा रास्ता दिखाया, तो उसमें पहले ही उनके सुरक्षा गार्ड्स फांद पड़े। भजनलाल संकरी सीढ़ियों में जब बुरी तरह फंसने लगे, तो वे सुरक्षा गार्ड्स पर झल्लाये, "अरे कभी तो मेरा पिंड छोड़ दिया करो। पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ से कुछ प्राइवेट बात करने के लिए गया, तो वहां भी तुम लोग फाट पड़े।" सुरक्षा गार्ड्स पर कोई असर नहीं हुआ और वे भजनलाल को संकरी सीढ़ियों में दबोचे नीचे उनके कक्ष में ले आये।

कृषि भवन की छत से उतर कर अपने कक्ष में भजनलाल आये कि उसके पहले दिल्ली दरबार ने 'रेक्स फोन' की घंटी बजा-बजाकर पूरे कृषि मंत्रालय की खटिया खड़ी कर दी थी। भजनलाल कक्ष में पहुंचे ही थे कि रेक्स की घंटी घनघना उठी। कांपते हुए हाथों से भजनलाल ने रेक्स टेलीफोन का चोंगा उठाया और कांपती हुई आवाज में "हैलो" बोला। दूसरी ओर से दिल्ली दरबार की तरफ से जार्ज भजनलाल पर दाना-पानी लेकर चढ़ बैठे, "भजनजी आप तो महीनों से भज रहे थे कि देवीलाल पर देवी अप्रसन्न हैं। २५ सितंबर को बोट क्लब पर भीड़ के नाम पर गधे लोटेंगे। यह भीड़ कहां से फाट पड़ी?" भजनलाल ने अपनी कांपती हुई आवाज को 'कंट्रोल' करते हुए कहा, "जार्ज साहब, यह आईबी आप को भीड़ की बाबत बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट कर रहा है। अरे मैंने

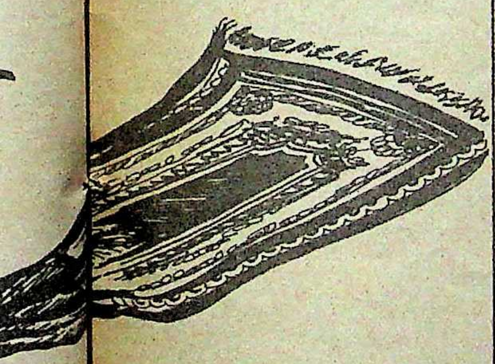

मंजिल दिल्ली ?
इस उड़न कालीन पर बैठिए...

कार्टून: केशव
सौजन्य: 'द हिंदू'

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को ले-दे कर पहले ही अपनी तरफ कर लिया है। यह भीड़ कुछ हजारों की है, जिसे लाखों में आईबी गिना रहा है।" जार्ज ने दरबार की तरफ से गुस्से का इजहार करते हुए टेलीफोन काट दिया और भजनलाल अपने छोर पर "जार्ज साहब...जार्ज साहब...सुनिये तो...।" चिल्लाते रहे। भजनलाल के कक्ष के बाहर खड़े पं० सुखराम और आर प्रभु खुशी से पागल हो रहे थे। प्रभु ने पं० सुखराम से गरमजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, "पंडितजी, यह भजनलाल का बच्चा मेरा पूरा उर्वरक मंत्रालय हजम कर गया और डकार तक नहीं ली। इसने मुझे न घर का रखा और न घाट का। अब इसे आटे-दाल का भाव देवीलाल की रैली से पता लग रहा है।" पं० सुखराम ने प्रभु की हां-में-हां मिलाते हुए कहा, "अरे प्रभु, तुझसे तो तेरा मंत्रालय ही इसने छीन लिया। चीनी पर कमीशन खाने के चक्कर में इस भजनलाल ने मेरा तो बंटाधार ही कर दिया। ऐसी जगह मुझे मारा जहां मुझे पानी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरी छुट्टी दरबार की चाकरी से होने ही वाली है।" पं० सुखराम बोल ही रहे थे कि कृषि भवन की छत से भजनलाल का एक कारिंदा भागता हुआ आया और कक्ष का दरवाजा खोलकर चिल्लाया, "नहीं उड़े। सिर पर बैठकर गुटरगूं कर रहे हैं।" भजनलाल ने जब अपने कारिंदे को डपटा, तो उसने पूरा वाक्य बोला, "सर, देवीलाल ने अपने ७५वें जन्मदिन पर ७५ सफेद कबूतर उड़ाये। लेकिन कुछ कबूतरों ने उड़ने से साफ इनकार कर दिया। वे देवीलाल के साफे पर बैठकर गुटरगूं कर रहे हैं। उड़ने से साफ इनकार कर दिया है। देवीलाल की चुनावी उड़ान के सारे मनसूबे धरे-के-धरे रह गये। ओम प्रकाश चौटाला और मुलायम सिंह यादव कबूतरों को उड़ाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कबूतर टस-से-मस नहीं हो रहे हैं।" भजनलाल कबूतरों के न उड़ने के रहस्य पर कोई कहानी दरबार को सुनाने के लिए गढ़ें कि छत से दूसरा कारिंदा भागता हुआ भजनलाल के सामने आ गिरा, "सर, मजा आ गया। अरुण नेहरू ऐंड कंपनी बोट क्लब का मंच छोड़कर भाग निकली। साथ में देवीलाल का एक सिपहसालार शरद यादव भी है।" भजनलाल खुशी से उछल पड़े, तो उनका गोल्डन फ्रेम का चश्मा जमीन पर गिर पड़ा। वर्मा ने भजनलाल को चश्मा पहनाया, तो उन्होंने रेक्स पर दिल्ली दरबार का नंबर घुमाया। लेकिन नंबर मिले कि उसके पहले तीसरा कारिंदा छत से नीचे आकर भजनलाल के सामने खड़ा हो गया, "हो गयी। जमकर हो गयी। सर, मुफ्ती और राजमाता सिंधिया में रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर जमकर हुई। वीपी सिंह ने रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर अपने प्रस्ताव के समर्थन में मुफ्ती मियां को बुलवाया। मुफ्ती थोड़ा बहक गये, तो राजमाता उन पर चढ़ बैठीं। अब चंद्रशेखर मामले को रफा-दफा कर रहे हैं।" भजनलाल जब ज्यादा खुश होते हैं, तो फौरन अंग्रेजी बोलने लगते हैं, "वैरी गुड...वैरी गुड। आई लाइक इट...।" इतने में रेक्स फोन का नंबर मिल गया। भजनलाल फोन पर खुशी से उछल पड़े, "जार्ज साहब, बहुत अच्छा हुआ कि देवीलाल की रैली में लाखों की भीड़ आयी। मंच पर जो जूतमपैजार हो रही है, कम-से-कम उसे तो वह देख रही है। जार्ज साहब आप दरबार को तुरंत बतायें कि भजनलाल की रणनीति पर ही देवीलाल की यह रैली हो रही है। भीड़ को हमने इसीलिए एकत्र किया था, ताकि वह देख सके कि देवीलाल के गिरोह में कितने मतभेद हैं। हम लोग अपने मकसद में पूरे खरे उतरे जार्ज साहब। अधिक-से-अधिक भीड़ एकत्र करने की मेरी ही योजना थी, ताकि वह देख सके कि देवीलाल क्या है!" जार्ज ने यह कह कर फोन रख दिया, "ठीक है, ठीक है। आप इस संबंध में दरबार को पूरी रिपोर्ट भेजें। लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा, तो दरबार के सामने उसे पेश नहीं किया जायेगा।"

"हुजूर यह भीड़ नहीं, जनता है। भीड़ की खरीद-फरोख्त हो सकती है, जनता की नहीं। आप जनता को भीड़ मानकर चलते रहे, इसी का नतीजा था कि हरियाणा में आपका पटरा साफ हो गया, अब लगता है सारे देश में आपकी खैर नहीं।"

भजनलाल ने अपने निजी सचिव वर्मा से कहा, "दरबार को देवीलाल की रैली पर तुरंत मेरी एक रिपोर्ट चाहिए। तुम एक रिपोर्ट मेरी ओर से अंग्रेजी में तैयार करो। उसके बाद मेरी हरियाणवी भाषा में उसका अनुवाद कराओ। मेरा अनुवाद ऊपर और उसका अंग्रेजी अनुवाद नीचे लगाकर तुरंत दरबार में पहुंचना जरूरी है।" वर्मा आदेश लेकर पीछे हटे ही थे कि कृषि भवन की छत से एक और कारिंदा उतर कर भजनलाल के सामने प्रस्तुत हो गया। भजनलाल बिगड़ पड़े, "बोलता क्यों नहीं? तुझे सांप क्यों सूंघ गया?" वह कारिंदा मरी हुई जुबान में बोला, "सर, रैली में नारा बुलंद हो गया है कि 'सिहासन खाली करो कि जनता आती है'।" भजनलाल बड़बड़ाये, "अरे भाई चुनाव तो अभी हुआ ही नही, तो यह सिहासन खाली करने का सवाल कैसे उठ गया!" कारिंदा कुछ नही बोला। लेकिन उसी समय दरवाजा खोलकर एक गोलमटोल आदमी आ खड़ा हुआ। भजनलाल भड़क उठे, "क्यों भाई, भीड़ जुटाऊ ठेकेदार। तूने तो मेरे साथ खासा दगा कर दिया। मैंने बोला था कि देवीलाल की रैली में ज्यादा भीड़ मत लाना। तुझको जो घाटा होगा, उसे मैं पूरा कर दूंगा।" भीड़ जुटाऊ ठेकेदार रुआंसा होकर बोला, "हुजूर यह भीड़ नहीं, जनता है। भीड़ की खरीद-फरोख्त हो सकती है, जनता की नहीं। आप जनता को भीड़ मान कर चलते रहे, इसी का नतीजा था कि हरियाणा में आपका पटरा साफ हो गया, अब लगता है सारे देश में आपकी खैर नहीं। अब भीड़ जनता बनती जा रही है, इसलिए मेरी भी खैर नहीं। मेरा भी धंधा चौपट समझिए।" इससे पहले कि भजनलाल कुरसी से उठकर उसे धर दबोचें, ठेकेदार फुर्ती से गरदन दबोच कर चंपत हो गया।

—दरबारी लाल

आपका भरोसेमंद फ़ैरेक्स,
अब 'स्वाद में सबसे आगे'!

जब आपका शिशु ४ महीने का हो जाए,
उसे नया स्वादिष्ट फ़ैरेक्स देना शुरू कीजिए.
शुरू में एक छोटे चम्मच फ़ैरेक्स को ३-४ छोटे चम्मच
गुनगुने पानी में मिलाकर दीजिए. फ़ैरेक्स अब पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट
और पौष्टिक है.

Delicious
Farex®
CEREAL WITH MILK
9 months
Give Farex Cereal with Milk with dal, kanji, suji or puddings.
12 months onwards

• ज़्यादा स्वादिष्ट
• ज़्यादा पौष्टिक

फ़ैरेक्स® - स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना.

GX/65/244 HIN

हिंदू सम्मेलन

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

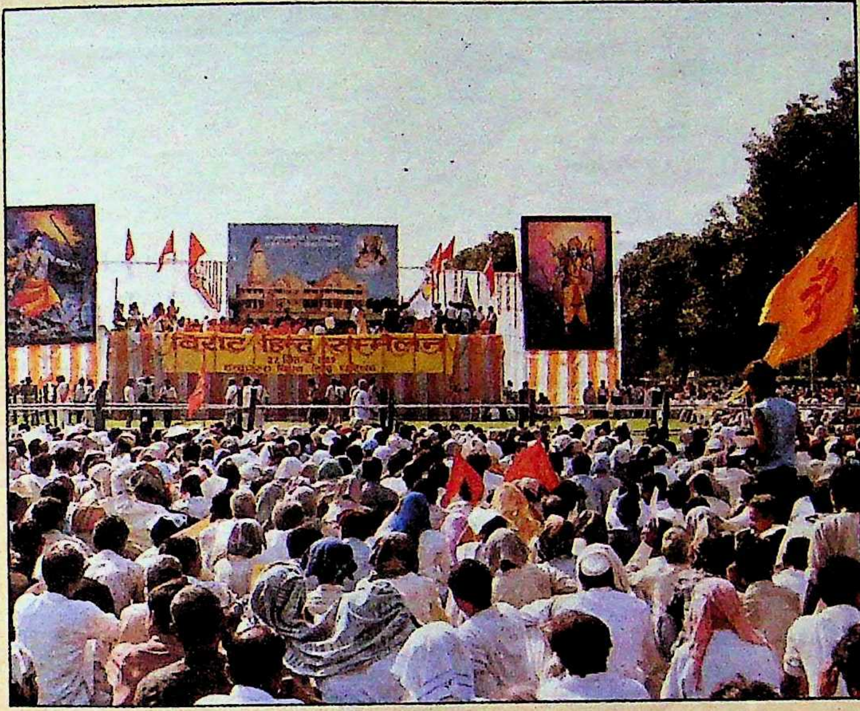

२२ सितंबर '८९ को बोट क्लब पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आये सैकड़ों साधु-संतों ने मिलकर सरकार को धमकी दी कि यदि उसने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनाने में बाधा डालने की जुर्रत की, तो 'हिंदू समाज' शांति की जगह क्रांति का उद्घोष करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने किया था। १५-१६ सितंबर से राजधानी में चल रही धर्मयात्रा का भी सम्मेलन के रूप में विधिवत समापन हुआ। सम्मेलन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और रामजन्म भूमि से अपना लगाव जतानेवाले नारों से माहौल गुंजाते हुए साधु संतों की बात सुनते रहे। हालांकि अदालत में लंबित मुकदमे के दौरान इस तरह के उत्तेजक सम्मेलन को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए वांछित नहीं माना जाता।

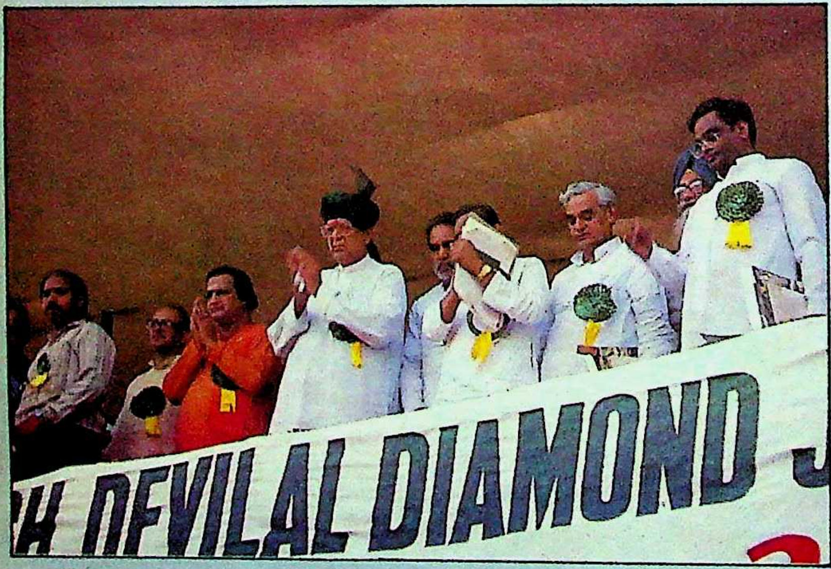

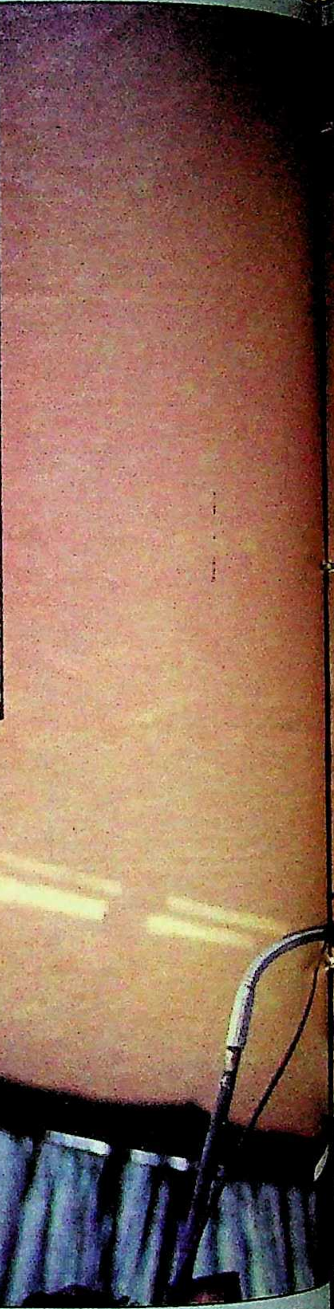

देवीलाल की रैली

२५ सितंबर '८९ को राष्ट्रपति भवन और संसद की दहलीज माने जानेवाले बोट क्लब पर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के ७५वें जन्म दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ। बोट क्लब पर बनाये गये विशाल मंच की दाहिनी ओर देवीलाल का २५ फुट लंबा कटआउट लगा था तथा मंच पर सीपीएम को छोड़ कर देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के जाने-माने नेता मौजूद थे, जिनमें वीपी सिंह, रामकृष्ण हेगड़े, अजीत सिंह, चंद्रशेखर, भाजपा संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, विजयाराजे सिंधिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव एम फारूकी, अकाली दल लोंगोवाल के अध्यक्ष सुरजीत सिंह बरनाला, असम गण परिषद सरकार के राजस्वमंत्री चंद्र अरंधारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के प्रतिनिधि और पूर्व सांसद एनवीएन सोमू की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। यह रैली विपक्षी एकता के प्रतीक बनते जा रहे देवीलाल को उनकी ७५वीं सालगिरह और ५० साल के संघर्षमय लोक जीवन पर उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित की गयी थी। इस दिन को देश के विपक्ष ने संघर्ष दिवस के रूप में मनाया। इस रैली की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामाराव ने की जो राष्ट्रीय मोर्चे तथा देवीलाल हीरक जयंती समारोह के अध्यक्ष भी हैं। रैली के हीरो देवीलाल सदा की तरह धोती-कुर्ते में ठीक ११ बजकर ५० मिनट पर मंच पर आये। एनटी रामाराव ने १२.१२ बजे देवीलाल को गुलाब की माला पहनायी और गले मिले तथा अटल बिहारी वाजपेयी और देवीलाल ने एक दूसरे को बाहों में लिया। अजीत सिंह ने गुलदस्ता भेंट किया। रामकृष्ण हेगड़े ने देवीलाल को कर्नाटक शैली की पगड़ी और चंदन की माला पहनायी। विजयाराजे

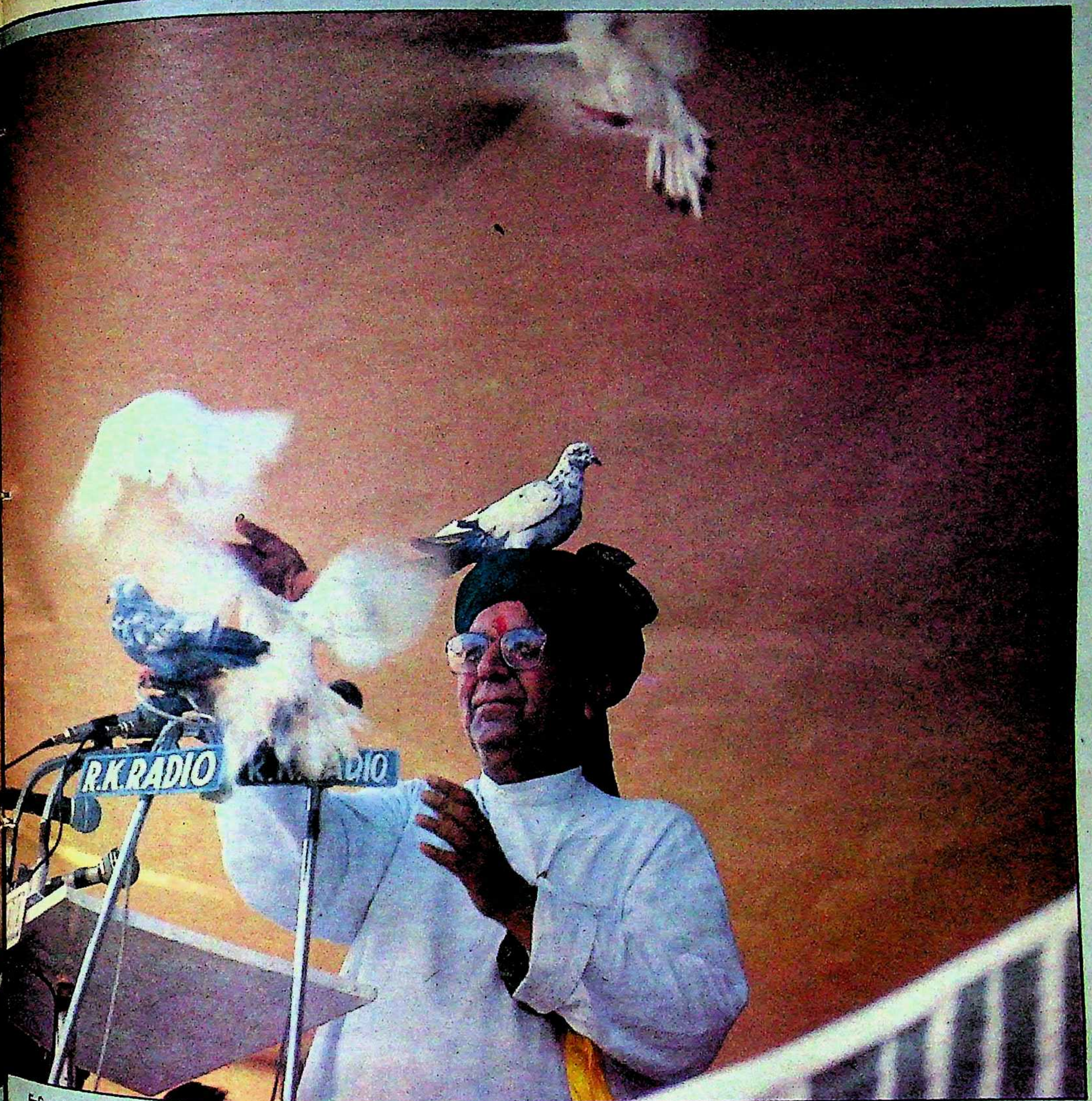

यक्ष भी हैं।
की तरह
र ५० मिनट
माराव ने
लाब की
तथा अटल
ल ने एक
जीत सिंह ने
ण हेगड़े ने
की पगड़ी और
जयाराजे

सिंधिया ने नारियल और माला भेंट की तथा वीपी सिंह ने देवीलाल को हरी पगड़ी पहनायी जो वे रैली के अंत तक पहने रहे। चंद्रशेखर ने उन्हें चांदी की प्लेट तथा अकाली सांसद जगजीत सिंह अरोड़ा ने शाल के साथ संघर्ष की प्रतीक लंबी तलवार भेंट की। बोट क्लब पर रफी किदवई मार्ग पर राजपथ के चौराहे से लेकर इंडियागेट तक दिखायी दे रही लाखों की भीड़ को संबोधित करने के पहले चौधरी देवीलाल ने ७५ कबूतर छोड़े।

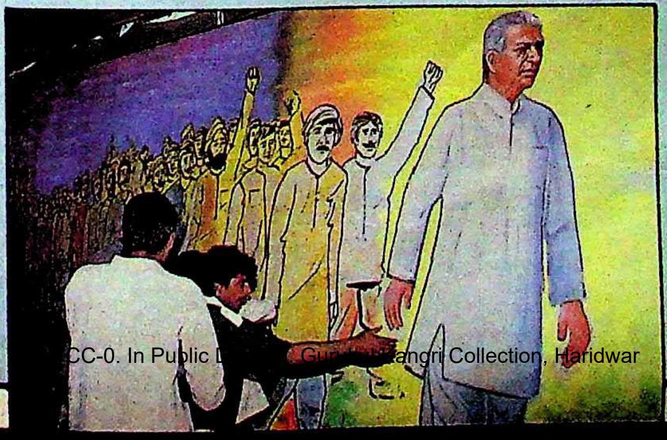

छाया :
एस पाल

CC-0. In Public D Gu angri Collection, Haridwar

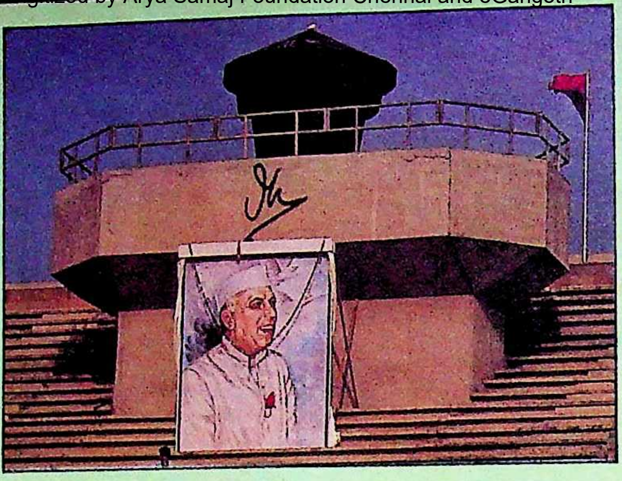

नेहरू शताब्दी खेल-मेला

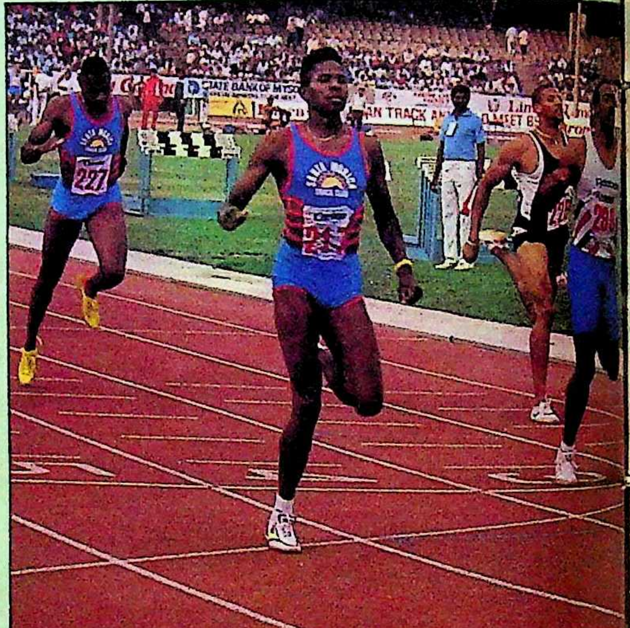

भारतीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा दिल्ली स्थित नेहरू स्टेडियम में १९ तथा २० सितंबर '८९ को नेहरू शताब्दी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग डेढ़ दर्जन विश्व तथा ओलंपिक चैंपियनों ने भाग लिया। १९ सितंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों (सबसे नीचे) के समय लगभग १५० अंतरराष्ट्रीय सितारों के बीच ६० विख्यात भारतीय एथलीट भी मौजूद थे, जिनमें कई यूरोपीय तथा एशियाई चैंपियन थे। नेहरू स्टेडियम में एथलेटिक्स मीट देखने आये दर्शकों को पहले दिन का आयोजन इसलिए फीका लगा, क्योंकि 'स्प्रिंट' के बादशाह तथा दुनिया के सबसे तेज धावक माने जानेवाले कार्ल लुइस को एनरीस बर्गर से पछाड़ खानी पड़ी। विदेशी खिलाड़ियों की ताकत, दमखम और दौड़ कौशल के बीच गौरवमय क्षण भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी आया। १५०० मीटर की दौड़ में सुपर स्टार एथलीटों के बीच रहनेवाले भारत के बहादुर प्रसाद ने २३ साल पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ दिखाया। एक अन्य भारतीय एथलीट शाइनी विलसन ने (ऊपर बायें) महिलाओं की ८०० मीटर दौड़ में जीत दर्ज की तथा दूसरे दिन ४०० मीटर की पुरुषों की दौड़ में अमरीका के डेनी एवरेट पहले नंबर पर रहे और केविन यंग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया (ऊपर दायें)। भारतीय स्टार पीटी ऊषा इस आयोजन में कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं पा सकीं। लेकिन महंगे टिकटों के कारण दर्शकों की कमी खलती रही, यहां तक कि एक ओर स्टेडियम खाली था, वहां मात्र 'दर्शक' जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर थी (सबसे ऊपर)।

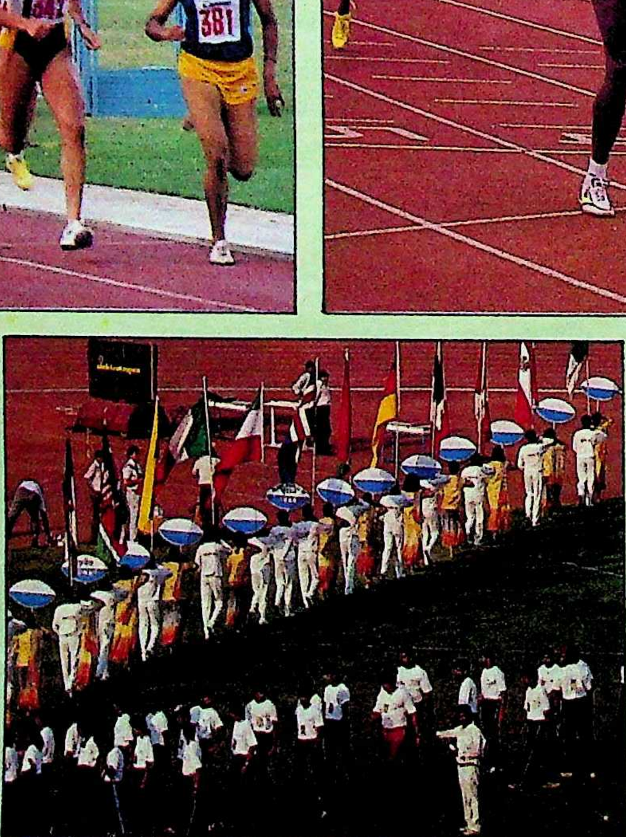

छाया :
एसपाल

ट्रांसफर-पोस्टिंग का फूलता-फलता धंधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के रिकार्ड के मुताबिक १ जनवरी, १९८९ से १६ अगस्त तक की अवधि में विधायकों, सासदों, मंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के जो ७९०५ पत्र प्राप्त हुए उनमें छह हजार से अधिक पत्र तबादलों और नियुक्तियों से संबद्ध हैं। तबादलों-नियुक्तियों में क्या निश्चित नियमों और प्रावधानों का पालन होता है ? नहीं होता है, तो क्यों ?

हालात से लगता है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग ने अब एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। जो भी सरकारी अफसर या कर्मचारी जितनी अच्छी लागत और 'जुगाड़' लगाता है, उतनी ही 'कमाऊ' पोस्ट उसे मिल जाती है। ट्रांसफर-पोस्टिंग के इस फूलते-फलते धंधे से नारायणदत्त तिवारी काफी दुखी हैं।

मुख्यमत्री सचिवालय के रिकार्ड के मुताबिक १ जनवरी, १९८९ से १६ अगस्त, १९८९ तक की अवधि में विधायकों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के जो ७९०५ पत्र प्राप्त हुए, उनमें छह हजार से अधिक पत्र किसी-न-किसी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले और नियुक्ति से ही संबद्ध हैं। दूसरे मंत्रियों और राज्यमंत्रियो के यहां प्राप्त पत्रों का भी यही औसत है। ज्यादातर पत्रों में सिफारिश करनेवाले इंका सांसदों और विधायकों ने यह तर्क दिया है कि चुनाव वर्ष होने के कारण यदि फलां अधिकारी को अमुक जगह नियुक्त कर दिया जाये, तो उससे चुनाव में पार्टी को लाभ पहुंचेगा।

कहा जाता है कि तबादलों के इस धंधे में सत्ता के दलाल तो कमा-खा ही रहे थे, इस बार ज्यादातर मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूके। स्वास्थ्यमंत्री गोपीनाथ दीक्षित के बारे में तो आम चर्चा है कि उन्होंने प्रदेश के १५१ डाक्टरों का एक साथ स्थानांतरण करने की टिप्पणी स्वास्थ्य सचिव केके बख्शी के पास भेज दी थी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने उसमें नुक्ता लगाकर उसे अस्वीकार कर दिया। अब चर्चा है कि स्वास्थ्यमंत्री उसे मुख्यमंत्री से स्वीकार करवाने की फिराक में हैं।

ट्रांसफर-पोस्टिंग के इस सीजन के दौरान ही ४ जुलाई को विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव ने राज्यपाल मुहम्मद उस्मान आरिफ को एक ज्ञापन देकर शिक्षामंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी, गृहमंत्री सुशीला रोहतगी, ग्राम्य विकास मंत्री श्यामसूरत उपाध्याय और ऊर्जामंत्री नरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग की थी। अनेक आरोपों में एक आरोप इन मंत्रियों पर भ्रष्ट अधिकारियों को मनचाही जगह स्थानांतरित करने का भी था।

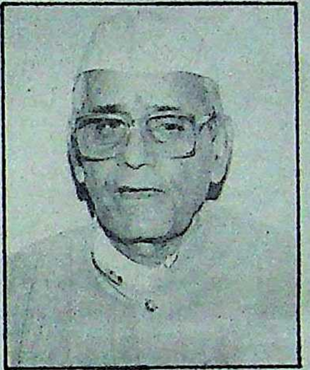

स्वास्थ्यमंत्री गोपीनाथ दीक्षित

स्वास्थ्यमंत्री के बारे में आम चर्चा है कि उन्होंने प्रदेश के १५१ डाक्टरों का एक साथ स्थानांतरण करने की टिप्पणी स्वास्थ्य सचिव केके बख्शी के पास भेज दी थी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने उसमें नुक्ता लगाकर उसे अस्वीकार कर दिया।

मुख्यमंत्री का सिरदर्द: आखिर, इस बार जनप्रतिनिधियों ने तबादलों और नियुक्तियों के लिए संबद्ध मंत्रियों के द्वार न जाकर मुख्यमंत्री को ही क्यों घेरा ? इसका कारण, वह परिपत्र बताया जाता है जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी किया गया है। इस परिपत्र में विधायकों, सांसदों तथा दूसरे जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की हर प्रकार की समस्याएं चाहे वे तबादलों से ही संबद्ध क्यों न हों, मुख्यमंत्री को अवगत करायें। यह परिपत्र चुनाव वर्ष को ध्यान में रखकर जारी किया गया था।

नियमानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण ३० जून तक समाप्त हो जाने चाहिए, विशेष परिस्थितियों में तबादले ३१ जुलाई तक किये जा सकते हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन इस बार तबादलों का सिलसिला अगस्त और सितंबर में भी जारी रहा।

मुख्यमंत्री की सज्जनता का लाभ उठाकर कई मंत्रियों और विभागाध्यक्षों ने इस बार तबादलों में दिल खोलकर 'मनमानी' की। आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि) के इंजीनियरों के स्थानांतरण की सूचियां राजभवन में बैठकर तैयार की गयीं, क्योंकि स्वयं राज्यपाल और उनके पुत्र कुछ अभियंताओं के तबादलों में 'दिलचस्पी' रखते थे। सानिवि के अधिशासी अभियंताओं के तबादलों की जो पहली सूची मई मास में जारी की गयी थी, उसमें स्पष्ट आदेश थे कि जिन अभियंताओं का वर्तमान पद से स्थानांतरण हो गया है और उन्हें नयी जगह नियुक्ति नहीं मिली है, वे वर्तमान पद से तत्काल चार्ज देकर नयी नियुक्ति की प्रतीक्षा करें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 'ऊपरी आदेश' से तीन अधिशासी अभियंताओं एसएन मिश्र, मुन्नीलाल सिंह और टीएन स्वामी का स्थानांतरण रद्द कर उन्हें वर्तमान स्थानों पर ही बना रहने दिया गया। विभागीय भाषा में ये तीनों स्थान 'कमाऊ' कहे जाते हैं। अधिशासी अभियंता ओडी सिंघल ने सानिवि के प्रमुख अभियंता धर्मवीर द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिसका खमियाजा उन्हें तीन वर्ष में तीसरी बार स्थानांतरण के रूप में भुगतना पड़ा, जबकि स्थानांतरण के बारे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा है, "सामान्यतः किसी पद पर अधिकारी अथवा कर्मचारी को यथासंभव तीन वर्ष तक अवश्य रखा जाये। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है जिससे अधिकारी की कार्यक्षमता को आंका जा सके।"

सानिवि में तबादलों पर उंगली उस समय उठी, जब ४ अगस्त, १९८९ को जारी स्थानांतरण सूची में २५ अधिशासी अभियंताओं के पूर्व स्थानांतरण आदेश निरस्त कर, उन्हें नये स्थानों पर नियुक्तियां दी गयीं या फिर अपने पूर्व स्थान पर उन्हें बने रहने दिया गया। तीन मास पूर्व वाराणसी के सेतु खंड से केएन तिवारी को बस्ती के अस्थाई खंड-१ में नियुक्त किया गया था,

लेकिन पता नहीं किस प्रेरणा से उन्हें ४ अगस्त को बस्ती में ही राजमार्ग जैसे फूलने फलनेवाले खंड में तैनात कर दिया गया। अभियंता टीपी सिंह का मामला तो काफी रोचक है। उनके विरुद्ध कई लाख के घपले के संबंध में जांच चल रही है। २५ जून को उन्हें इलाहाबाद से स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन ४ अगस्त को उन्हें पूर्ववत इलाहाबाद में ही नियुक्त कर दिया गया। ऐसे ही एक अभियंता हैं—राजबहादुर सिंह। उन्हें एक वर्ष पूर्व सड़क निर्माण में किये गये घपले के कारण निलंबित कर दिया गया था। अपने निलंबन के विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस बीच राजबहादुर सिंह को दंडस्वरूप 'आफिस अटैच' कर दिया गया। लेकिन ४ अगस्त को उनको गोरखपुर के प्रांतीय खंड जैसे कमाऊ पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री अम्मार रिजवी कहते हैं, "प्रजातंत्र में जन प्रतिनिधियों की बात को सम्मान दिया जाना आवश्यक है, फिर इस पोस्टिंग के लिए तो वीरबहादुर सिंह के पुत्र फतेहबहादुर सिंह की सिफारिश थी।"

आरोपों के बावजूद : सानिवि में ऐसे अनेक प्रकरण हैं। फर्रुखाबाद में तैनात अधिशासी अभियंता उमेश दीक्षित के विरुद्ध जीटी रोड राजमार्ग बनवाने में एक करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया। उमेश दीक्षित पर यह भी आरोप है कि जीटी रोड की ४ किलोमीटर सड़क का फर्जी निर्माण कागजों में दिखाकर ४६ लाख रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। उमेश दीक्षित के विरुद्ध जांच शुरू की गयी। जांच में कोई बाधा न पड़े, इसलिए प्रमुख अभियंता ने उनका वहां से स्थानांतरण कर दिया। लेकिन प्रदेश के राज्यपाल और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की भारी भरकम सिफारिश के कारण स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिये गये।

गृहमंत्री सुशीला रोहतगी

ग्राम्य विकास मंत्री श्याम सूरत

सत्यपाल यादव ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर गृहमंत्री सुशीला रोहतगी और ग्राम्यविकास मंत्री श्यामसूरत उपाध्याय को बर्खास्त करने की मांग की थी। इन मंत्रियों पर भ्रष्ट अधिकारियों को मनचाही जगह स्थानांतरित्त करने का आरोप था।

सानिवि के अभियंताओं की ट्रांसफर-पोस्टिंग में प्रदेश के राज्यपाल मुहम्मद उस्मान आरिफ और उनके पुत्र इरफान आरिफ की कथित दखलंदाजी पूरे विभाग में चर्चित है। अभियंता एके कौशिक, १९७६ से राजभवन के रखरखाव के लिए नियुक्त हैं। पहले वे अवर अभियंता थे, बाद में उन्हें सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत कर राजभवन में ही रहने दिया गया। नियमानुसार पदोन्नति के बाद दूसरी जगह स्थानांतरण आवश्यक है।

पंचायतराज विभाग : पंचायतराज विभाग में भी इस बार ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर जबरदस्त मारा-मारी हुई। पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेठी की एक सार्वजनिक सभा में इस विभाग की जबरदस्त खिंचाई की थी। चूंकि, इसी विभाग पर जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरा करने की जिम्मेदारी है, इसीलिए हर जनप्रतिनिधि यह चाहता है कि उसका मनचाहा अभियंता और अधिकारी 'कमाऊ' पोस्ट पर तैनात हो जाये।

पंचायत मंत्रालय के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरईएस) के प्रमुख अभियंता ईएमआर सिद्दीकी के विरुद्ध लाखों रुपए के गोलमाल, नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से लोगों को नौकरी देने तथा निर्माण कार्यों में घोटाले के गंभीर आरोप विधानसभा तक में लग चुके हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन इस जांच का कोई फल निकलेगा, इस पर विभाग के व्यक्तियों को शक है। आरईएस का मुख्य कार्य गांवों में सड़कों का निर्माण तथा अन्य विकास कार्य करना है। इसी विभाग के एक अन्य अभियंता एनके अग्रवाल को हाल में कार्मिक विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात किया गया है। अग्रवाल वर्ष १९८३ से १९८७ तक सुल्तानपुर में अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त थे। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्य की जिम्मेदारी अग्रवाल पर ही थी।

वर्ष, १९८४ में अग्रवाल ने अमेठी के विकास कार्य के लिए विभाग से कई लाख रुपए अग्रिम प्राप्त कर खर्च दिखा दिया। अग्रिम धन के लिए उन्होंने विभाग से कहा कि मंत्री ने इसके मौखिक आदेश दिये हैं। तत्कालीन मंत्री पीके शर्मा को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने लिखित रूप से यह सूचित किया कि उन्होंने अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए अग्रवाल को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया था। अग्रवाल के विरुद्ध जांच शुरू हुई। अमेठी संसदीय क्षेत्र में १९८५-८६ के दौरान १६९ स्कूल-भवन बनाने का कार्य आरईएस को दिया गया। वर्ष, १९८७ में अग्रवाल की ओर से शासन को जो रिपोर्ट भेजी गयी, उसमें सभी १६९ भवनों का पूर्ण हो जाना बताया गया था, जबकि स्कूल-भवनों का निर्माण कार्य अब भी चल रहा है। जो भवन बन चुके हैं, उनमें से नमूने के तौर पर चार की जांच करायी गयी, तो दो भवनों में लगायी गयी सामग्री अत्यंत निम्न स्तर की पायी गयी। भवन निर्माण करनेवाले ठेकेदारों ने बेईमानी स्वीकार कर धन भी जमा कर दिया, लेकिन अभियंता को पुरस्कार-स्वरूप मुख्यालय में वैयक्तिक सहायक का पद दे दिया गया है। अब अग्रवाल भ्रष्ट अभियंताओं की शिकायतों की जांच करेंगे।

एक अन्य अधिशासी अभियंता एमएस खान जब फर्रुखाबाद में नियुक्त थे, तब उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करने गये संख्या-अधिकारी पर खान के इशारे पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी थी। इसी के बाद गबन के आरोप में उन्हें मुख्यालय लखनऊ में 'सूखी जगह' अटैच कर दिया गया। एमएस खान, रामपुर के विधायक मुहम्मद आजम खां के भाई हैं। खान उक्त जगह रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना तबादला हरदोई करा लिया, लेकिन वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें 'ज्वाइन' नहीं करने दिया, तो उनका स्थानांतरण पीलीभीत कर दिया गया। इस वर्ष श्रममंत्री सईदुल हसन ने सिफारिश करके खान को अपने जिले बुलंदशहर में नियुक्त करा लिया।

मुख्यमंत्री की कुरसी पर नजर गड़ाये बैठे सिंचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने इस बार विभागीय अभियंताओं के स्थानांतरण अपने स्तर से नहीं किये। सारी जिम्मेदारी उन्होंने विभागीय सचिव और तीनों प्रमुख अभियंताओं को सौंप दी

थी। लोकपति ने यह इसलिए किया, ताकि किसी विवाद या बदनामी से बचे रहें।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सैयद इश्तियाक अहमद के अवकाश ग्रहण करने पर मुख्य अभियंता एसपी माथुर को लोकपति त्रिपाठी प्रमुख अभियंता के पद पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन माथुर वरीयताक्रम में नीचे थे। माथुर को 'एडजस्ट' करने के लिए सिंचाई मंत्री ने प्रमुख अभियंता (बाढ़ नियंत्रण) का एक नया पद सृजित करा लिया। लोकपति की इच्छानुसार मनचाहे अभियंताओं के तबादले करने में इस बार माथुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

सिंचाई खंड हल्द्वानी के विवादास्पद अभियंता केपी सक्सेना को २४ जून, १९८९ को लखनऊ स्थित केंद्रीय परिकल्प निदेशालय में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन २० दिन बाद ही उन्हें परियोजना समन्वय (विश्व बैंक) के कार्यालय से सम्वद्ध कर दिया गया। अभियंता सैयद अतहर हुसैन को गत वर्ष शारदा सहायक खंड २८ (हैदरगढ़, बाराबंकी) से हटाकर सिंचाई खंड फैजाबाद में डाल दिया गया था। उनके स्थान पर धर्मचंद्र सामंत को बिठाया गया। विभाग के लोग इस पद को 'दुधारू' कहते हैं। एक बार स्थानांतरण आदेश हो जाने के बाद दो दर्जन से अधिक अधिशासी अभियंताओं के नियुक्ति स्थान 'ऊपरी आदेश' पर या तो बदले गये या फिर उन्हें पूर्व स्थान पर चुनाव वर्ष में बने रहने दिया गया। संत प्रकाश शर्मा नामक अभियंता को शारदा सहायक खंड-४९ (सुल्तानपुर) से पहले शारदा नहर हरदोई स्थानांतरित किया गया, लेकिन दो दिन बाद ही उन्हें सरयू नहर खंड-१ नानपारा (बहराइच) जैसे दुधारू पद पर नियुक्त कर दिया गया। शारदा सहायक के मुख्य अभियंता कार्यालय से सम्वद्ध श्रीनिवास दुबे को एक वर्ष पूर्व ही पदोन्नति दी गयी थी। नियमानुसार उन्हे दो वर्ष और 'नानवर्किंग डिवीजन' (विभाग में नान वर्किंग और वर्किंग डिवीजन क्रमशः सूखे और कमाऊ डिवीजन कहे जाते हैं) में रहना था। पहले दुबे का तबादला शारदा सहायक खंड-४० में हुआ, फिर 'प्राइज पोस्टिंग' देकर उन्हें सरयू नहर खंड-४ में बहराइच भेज दिया गया। सत्यनारायण गर्ग को पहले सिंचाई खंड बरेली से सिंचाई खंड शारदा नहर भेजा गया, किन्तु बाद में 'ऊपरी आदेश' पर उन्हें रायबरेली में शारदा सहायक खंड-४१ जैसी अच्छी नियुक्ति मिल गयी। जोड़-तोड़ और धन-बल के आधार पर सिंचाई विभाग में 'प्राइज पोस्टिंग' पानेवाले अभियंताओं की सूची काफी लम्बी है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए शासन का स्पष्ट आदेश है कि हर अधिकारी को १५ वर्षों की सेवा में कम-से-कम छह वर्षों तक नान वर्किंग पदों पर काम करना होगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या काफी है, जिन्होंने अपनी पहुंच या अन्य तरीकों के जरिए शासन के इस आदेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लखनऊ डिवीजन के कार्यकारी इंजीनियर-सीपी सिंह, कार्यकारी इंजीनियर (एलआईडी) कानपुर-डीपी सिंह, कार्यकारी इंजीनियर (एलआईडी) इलाहाबाद—वीके खरे और लखनऊ के १२वें सर्किल के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, उदयराज सिंह ऐसे ही अफसर हैं, जिन्होंने किसी भी नान वर्किंग पद पर एक भी दिन काम नहीं किया। प्रतापगढ़ के सुप्रिटेंडेंट बीबी सिंह ने अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ ८ मासों तक ऐसे पद पर कार्य किया है।

पुलिस विभाग: तबादलों की इस आपाधापी में भला पुलिस विभाग पीछे कैसे रहता। आज हर विधायक और सांसद यह महसूस करता है कि उसके क्षेत्र का दरोगा चुनाव में मदद कर उसे जिता सकता है। पुलिस मुख्यालय के रिकार्ड के अनुसार मई, जून और जुलाई के तीन महीनों में जनप्रतिनिधियों के ४०२५ प्रार्थनापत्रों में ८५ प्रतिशत से अधिक पत्र दरोगा और इंस्पेक्टर की नियुक्ति से सम्बद्ध थे। दरअसल, गृहमंत्री सुशीला रोहतगी, ट्रांसफर-पोस्टिंग में इसलिए दिलचस्पी नहीं लेती हैं, क्योंकि उनके लिखित आदेश तक का पालन कोई अधिकारी नहीं करता है। विभाग के अधिकारी वास्तविक गृहमंत्री तो गृहसचिव संत कुमार त्रिपाठी को ही मानते हैं। शायद यही कारण है कि विपक्ष और सत्तापक्ष के कुछ विधायकों को पुलिस-विभाग की तबादला-सूची में जातीयता की बू आने लगी है।

राज्यपाल मु० उस्मान आरिफ

राज्यपाल के पुत्र इरफान आरिफ

आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के स्थानांतरण की सूचियां राजभवन में बैठकर तैयार की गयीं, क्योंकि स्वयं राज्यपाल और उनके पुत्र कुछ अभियंताओं के तबादलों में 'दिलचस्पी' रखते थे।

विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव कुछ उदाहरण देते हैं। मसलन पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के पद पर तैनात हनुमान प्रसाद त्रिपाठी को पदोन्नति देकर जब उपमहानिरीक्षक बनाया गया, तब उन्हें रेलवे पुलिस इलाहाबाद में ही नियुक्त कर दिया गया, जबकि नियमानुसार पदोन्नति के तत्काल बाद वरिष्ठ पद नहीं दिया जाता है। वह भी तब, जब त्रिपाठी के विरुद्ध हुई जांच के आठ मामलों में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति है। ठीक इसके विपरीत आईपीएस अधिकारी अजय सिंह का मामला है। वर्तमान में वे राज्य विद्युत परिषद में पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन) के पद पर तैनात हैं। उनके विरुद्ध १९८७ में विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए थे। लेकिन न तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई और न ही विभाग ने शासन को इस संदर्भ में कोई प्रतिवेदन ही भेजा। नियमानुसार छह मास के अन्दर विभागीय कार्रवाई हो जानी चाहिए और यदि कार्रवाई में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, तो संबद्ध अधिकारी को पदोन्नति दे दी जानी चाहिए। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने अगस्त, १९८८ में अजय सिंह का चयन उपमहानिरीक्षक पद के लिए कर लिया। इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति न देकर उस अधिकारी को पदोन्नति दी गयी, जिसके विरुद्ध आठ मामलों में विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है।

आईपीएस अधिकारी जीएस गुंगेश १९८४ से अपराध शाखा में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थे। इस वर्ष उन्हें हरिजन प्रकोष्ठ में भेज दिया गया। क्या कारण सिर्फ यह है कि वे ईमानदार हैं, हरियाणा के जाट हैं, शासन स्तर पर उनकी सिफारिश करनेवाला कोई नहीं है? स्वर्गीय वीरबहादुर के विश्वासपात्र डीबी राय को पुलिस अधीक्षक (कानपुर नगर) के पद से दो वर्ष के अंदर ही इसी जुलाई में हटाकर उनके स्थान पर आरआर भटनागर को भेजा गया। जब

वीरबहादुर समर्थकों ने हायतौबा की, तो राय को फिर उसी पद पर नियुक्त करने के आदेश मुख्यमंत्री को देने पड़े। आरआर भटनागर को कानपुर में पुलिस अधीक्षक (यातायात) के पद पर नियुक्त करने के लिए एएल बनर्जी जैसे ईमानदार और तेजतर्रार अधिकारी को हटाकर पीएसी मुरादाबाद में फेंक दिया गया। कुंभ मेले में उल्लेखनीय कर्तव्य परायणता और कुशलता का परिचय देनेवाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीएन राय की नियुक्ति में उनके सराहनीय कार्य की उपेक्षा की गयी।

एक अन्य आईपीएस अधिकारी बंशीलाल तो पूरे प्रदेश में चर्चित हो चुके हैं। दो मास पूर्व तक वे लखनऊ में सिंचाई प्रकोष्ठ में पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त थे। लखनऊ के अलीगंज इलाके में उन्होंने आलीशान कोठी बनवायी है। कोठी के एक हिस्से में उनकी पत्नी स्कूल चला रही हैं। इतनी आलीशान कोठी कैसे बनी, इसकी जांच भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग कर रहा है। बंशीलाल के रोब से पूरा इलाका थर्राता है। पिछले वर्ष अगस्त में उन्होंने डंडे के बल पर एक विधवा के मकान पर बलात कब्जा कर लिया। उनके अत्याचारों से निजात पाने के लिए क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के यहां धरना तक दिया। बंशीलाल के विरुद्ध जांच हुई। आरोप सही पाये गये। उन्हें लखनऊ से मुरादाबाद प्रशिक्षण विद्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन बंशीलाल लखनऊ छोड़ना नहीं चाहते हैं। बीमारी के आधार पर उन्होंने छुट्टी ले रखी है। राज्यमंत्री ब्रजेन्द्रपाल सिंह यादव लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं कि बंशीलाल का स्थानांतरण रद्द कर उन्हें लखनऊ में ही रहने दिया जाये।

खानि मंत्री अम्मार रिजवी

अम्मार रिजवी कहते हैं, "प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों की बात को सम्मान दिया जाना आवश्यक है, फिर इस पोस्टिंग के लिए तो वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर सिंह की सिफारिश थी।"

पुलिस विभाग का ही उदाहरण सारे तबादलों और नियुक्तियों की कलई खोल देता है। यह मामला विभाग के बहुचर्चित इंस्पेक्टर कोमल मिश्र का है। १९८६ में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में इंस्पेक्टर कोमल मिश्र को दोषी पाया गया था। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जेएन चतुर्वेदी ने सारे मामले की विस्तृत जांच के बाद कोमल मिश्र को बर्खास्त कर दिया था। उस समय कोमल मिश्र की जबरदस्त पैरवी लोकपति त्रिपाठी ने की थी, लेकिन वीरबहादुर सिंह के सामने उनकी एक न चली। अब वीरबहादुर के निधन के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर न केवल कोमल मिश्र को वापस सेवा में ले लिया गया, वरन उन्हें पहले झांसी और अब इसी २ सितम्बर को उन्नाव जैसे महत्वपूर्ण जिले में इंस्पेक्टर पद पर तैनात कर दिया गया है।

ऊर्जा विभाग: तबादले की इस मौसमी वर्षा में हाथ धोने से भला ऊर्जा विभाग पीछे क्यों रहता। इस वर्षा के छींटे उर्जामंत्री नरेन्द्र सिंह पर कम, विद्युत परिषद के हरफनमौला अध्यक्ष भूपाल सिंह पर कुछ ज्यादा ही पड़े हैं। भ्रष्ट चर्चित अभियंताओं में ज्यादातर को इस बार 'प्राइज पोस्टिंग' दी गयी। गोंडा में अधिशासी अभियंता (विद्युत) के पद पर तैनात ग्यासुद्दीन को हटाने के लिए जिले के सभी विधायकों और सासदों ने लिखित शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि अधिशासी अभियंता के भ्रष्टाचार के कारण जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों की इस संयुक्त शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और एक शासनादेश के जरिये ग्यासुद्दीन का स्थानांतरण कर दिया गया। उनके स्थान पर टीडी सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन पंद्रह दिन बाद ही ऊर्जामंत्री नरेन्द्र सिंह के विशेष निर्देश पर ग्यासुद्दीन को पुन: गोंडा में नियुक्त कर दिया गया। अब राज्यमंत्री जगदम्बिका पाल, सांसद आनंद सिंह, विधायक रामबहादुर सिंह, रामपाल सिंह, राम विशुन आजाद तथा गोंडा जिला इंका अध्यक्ष मुरलीधर मुनीम लगातार ग्यासुद्दीन के विरुद्ध ऊर्जामंत्री को शिकायतें भेज रहे हैं, लेकिन मंत्रीजी चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके विपरीत फैजाबाद में तैनात ईमानदार और तेज अधिशासी अभियंता केवलराम कृष्णानी को मात्र एक वर्ष में ही इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि स्थानीय सांसद निर्मल खत्री उस स्थान पर अपने चहेते अभियंता को नियुक्त कराना चाहते थे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। ऊर्जामंत्री स्वीकार करते हैं कि कृष्णानी का कार्य अच्छा था। इसके बावजूद कृष्णानी को कोई अच्छी नियुक्ति नहीं दी गयी।

एक अधिशासी अभियंता बीएस शर्मा की सेवाएं ३१ जुलाई १९८६ को समाप्त कर दी गयी थीं। शर्मा १९८० में गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। ५ मई, १९८० को उनका स्थानांतरण कार्मशियल डिवीजन इलाहाबाद में किया गया, लेकिन शर्मा, गाजियाबाद की कमाऊ सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने इलाहाबाद जाने से इनकार कर दिया, तो ६ जून, १९८० को उन्हें एसू (इलाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग) में जाने का आदेश हुआ, लेकिन शर्मा वहां भी नहीं गये। तब विद्युत परिषद ने १७ मई, १९८२ को शर्मा का तबादला ओबरा कर दिया। चार वर्ष तक जब शर्मा, गाजियाबाद से टस-से-मस न हुए, तब ३१ जुलाई १९८६ को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं।

शर्मा, भूपाल सिंह के खास आदमी हैं। भूपाल सिंह जब विद्युत परिषद के चेयरमैन बन गये, तो इसी ५ जून को उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रखकर बीएस शर्मा को सेवा में वापस ले लिया और उन्हें गाजियाबाद में ही अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त कर दिया। यही नहीं, बीएस शर्मा की नौ वर्ष की अनुपस्थिति में उनकी सेवाएं बरकरार मानकर उन्हें पदोन्नति देने के लिए भूपाल सिंह ने एक विभागीय समिति भी गठित कर दी है।

सिंचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी

मुख्यमंत्री की कुरसी पर नजर गड़ाये बैठे सिंचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने इस बार विभागीय अभियंताओं के स्थानांतरण अपने स्तर से नहीं किये। लोकपति ने यह इसलिए किया, ताकि किसी विवाद या बदनामी से बचे रहें।

गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर और आगरा में पिछले दिनों जितने भी अभियंता नियुक्त किये गये हैं, उनमें ज्यादातर के

ऊर्जामंत्री
नरेंद्र
सिंह

राविप के
अध्यक्ष
भूपाल सिंह

तबादले की इस मौसमी वर्षा में हाथ धोने से भला ऊर्जा विभाग पीछे क्यों रहता। इस वर्षा के छींटे ऊर्जा मंत्री नरेंद्र सिंह पर कम, विद्युत परिषद के हरफनमौला अध्यक्ष भूपाल सिंह पर कुछ ज्यादा ही पड़े हैं।

बारे में कहा जाता है कि उनकी नियुक्ति में भूपाल सिंह ने व्यक्तिगत दिलचस्पी ली है। विद्युत परिषद के अभियंता बताते हैं कि पता नहीं किन कारणों से ऊर्जामंत्री नरेन्द्र सिंह परिषद अध्यक्ष भूपाल सिंह से दबे रहते हैं। इसी कारण भूपाल सिंह मनमानी करते हैं।

स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य विभाग के विवादास्पद तबादले इस वर्ष पूरे प्रदेश में चर्चा के विषय बने रहे। लखीमपुर खीरी में तो एक साथ दो-दो मुख्यचिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के आदेश हो गये। एक स्वास्थ्यमंत्री का चहेता, तो दूसरा स्वास्थ्य निदेशक का। नतीजतन, दोनों चिकित्साधिकारियों के बीच चार्ज लेने के प्रश्न पर न केवल मारपीट हुई, वरन गोलियां तक चलीं।

इसी प्रकार रायबरेली के सीएमओ डा० एसके खरे को स्वास्थ्य सलाहकार के पद पर बरेली स्थानांतरित किया गया। रायबरेली में उनके स्थान पर डा० वाजपेयी ने चार्ज भी ले लिया, लेकिन स्वास्थ्यमंत्री के विशेष आदेश पर डा० खरे का तबादला रोक दिया गया। आजमगढ़ और मऊ जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारियों का एक दूसरे के स्थान पर आठ मास में चार बार तबादला हो चुका है।

लखनऊ में तैनात औषधि निरीक्षक एके जैन का मामला तो काफी रोचक है। स्वास्थ्यमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने जैन को आदेश दिया कि लखनऊ मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल को आपूर्ति की जा रही पट्टियों (बैंडेज) के नमूने लेकर जांच करें। पट्टियों की सप्लाई मेरीनो वूलेन मिल कानपुर द्वारा की जा रही थी। जैन ने दोनों अस्पतालों से पट्टियों के नमूने लिये। जांच होने पर वे अत्यंत घटिया स्तर की पायी गयीं। इसी के बाद मेरीनो वूलेन मिल के मालिकों ने स्वास्थ्यमंत्री तक पहुंच बनायी और चार दिन बाद ही औषधि निरीक्षक एके जैन को आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। जैन के स्थान पर आगरा के जिन एमएन गुप्त को नियुक्त किया गया, उनके विरुद्ध नकली दवा बनवाने के आरोप की जांच सतर्कता विभाग ने की थी, जिसमें दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है। स्वास्थ्य निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैन के स्थान पर गुप्त की नियुक्ति स्वास्थ्यमंत्री के पुत्र की सिफारिश पर हुई है। उन्हीं के आग्रह पर पट्टियों की जांच का कार्य भी गुप्त को सौंपा गया है। उधर एके जैन के स्थानांतरण के विरोध में सभी औषधि नियंत्रण निरीक्षक एक जुट हो गये। नतीजतन, स्वास्थ्यमंत्री को लखनऊ में जैन और गुप्त दोनों को तैनात करना पड़ा।

स्वास्थ्यमंत्री के दामाद राजीव वाजपेयी को दबाव में हरदोई जिला चिकित्सालय के रेडियोलाजिस्ट डा० ओपी मिश्र को हटाकर उनके स्थान पर डा० वाजपेयी को नियुक्त कर दिया गया। जब स्वास्थ्य सचिव केके बख्शी को इसकी जानकारी मिली, तब उन्होंने इस स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। इसी के बाद सचिव और मंत्री में ठन गयी। बावजूद इस तनातनी के डा० वाजपेयी अभी भी हरदोई में जमे हैं।

मंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने १० अगस्त, १९८९ को पत्रांक संख्या-८०८ के द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सचिव के स्तर से मुख्यचिकित्सा अधिकारियों, उनके समकक्ष या सामान्य श्रेणी के जिन डाक्टरों के स्थानांतरण किये गये हैं, वे सभी नियम के विरुद्ध हैं, क्योंकि उन पर 'मेरा' (स्वास्थ्यमंत्री का) अनुमोदन नहीं है। भविष्य में मेरे अनुमोदन के बिना कोई स्थानांतरण न करें।

तबादलों में स्वास्थ्यमंत्री, उनके पुत्र, दामाद और जनसम्पर्क अधिकारी की दखलंदाजी का नतीजा यह हुआ कि अब कोई भी डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है। प्रदेश के शहरी अस्पतालों में रिजर्व ड्यूटी मेडिकल आफिसर (आरडीएमओ) के ९० पद हैं। नियमानुसार, इस पद पर उसी डाक्टर को नियुक्त किया जाता है, जिसका कम-से-कम ५ वर्ष काम करने का अनुभव हो। पर सारे नियमों को नजरंदाज कर स्वास्थ्यमंत्री ने नये भर्ती होनेवाले डाक्टरों को रिजर्व ड्यूटी मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्त करने के आदेश दे दिये। इन सभी डाक्टरों को पांच वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में नियुक्त किया जाना था। स्वास्थ्यमंत्री ने ऐसे लगभग ३५० डाक्टरों को रिजर्व ड्यूटी मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्त करने के आदेश दिये। अब यह स्वास्थ्य निदेशक का सिरदर्द है कि वे इन ३५० डाक्टरों को शहर के अस्पतालों में कहां खपायें।

अपने विशेषाधिकार का प्रयोगकर स्वास्थ्यमंत्री ने डाक्टर आरएस वाजपेयी को कार्यवाहक स्वास्थ्य निदेशक बना दिया। इसी तरह डा० पीडीपी माथुर को निदेशक (परिवार नियोजन) नियुक्त कर दिया। जबकि ये दोनों अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (नियोजन) डा० एसके सक्सेना से जूनियर हैं। स्वास्थ्य विभाग के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब बिना एमबीबीएस डिग्रीधारक को स्वास्थ्य निदेशक का महत्वपूर्ण पद दिया गया है। डाक्टर वाजपेयी आयुर्वेद के डाक्टर हैं। आयुर्वेद का एक अलग निदेशालय भी है, लेकिन स्वास्थ्यमंत्री के कृपापात्र डा० वाजपेयी को आयुर्वेद निदेशालय के बजाय स्वास्थ्य निदेशालय में निदेशक बना दिया गया।

उत्तर प्रदेश में धन बल और पहुंच के आधार पर अधिकारियों द्वारा मनचाही जगह प्राप्त करने का जो सिलसिला पिछले पांच वर्ष से तेज हुआ है, यह उसी का परिणाम है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कोई भी पत्रावली बिना 'वजन' रखे, आगे बढ़ती ही नहीं है। सरकार पर नौकरशाही हावी हो गयी है, क्योंकि हर 'तिकड़मबाज' अफसर की 'पैरवी' के लिए राजनेता जी-जान एक कर देते हैं।

—अजय कुमार, निशीथ जोशी

देवीलाल की रैली

वर्चस्व का अभूतपूर्व प्रदर्शन

जिंदाबाद
भावी राजनीतिक जनक और विपक्षी एकता के प्रतीक
चौ. देवीलाल
मुख्य मन्त्री हरियाणा
हर हाथ को काम
हर पेट के लिए रोटी
सब बातें खोटी
चौ. देवीलाल

जनसागर का ज्वार: बोट क्लब पर उमड़ी अभूतपूर्व भीड़

छाया: सुनील सक्सेना

देवीलाल की हीरक जयंती के समारोह के अवसर पर दिल्ली के बोट क्लब पर जुटे अभूतपूर्व जनसमूह ने विपक्ष को विभाजित करने के सपने संजोनेवाले शासक दल (कांग्रेस) के होश उड़ा दिये हैं। बदहवासी का आलम कुछ ऐसा रहा कि देवीलाल के पुराने प्रतिद्वंद्वी केंद्रीय कृषिमंत्री भजनलाल को लाखों की रैली में मात्र हजारों की भीड़ नजर आयी। आधुनिक तकनीकी युग में, जहां रैली आदि की विशालता का अनुमान लगाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद रहना आवश्यक नही होता, बल्कि वीडियो फिल्मों के माध्यम से भी जायजा लिया जा सकता है, वहां माननीय मंत्री महोदय की पूर्वग्रहग्रस्त सूरदासी टिप्पणी न केवल उनके तथा उनकी पार्टी के दिवास्वप्न की द्योतक है, बल्कि उनकी बेचैनी और बौखलाहट की भी सूचक है। विशेषकर इसलिए, क्योंकि इस विशाल रैली का वीडियोकरण न सिर्फ देवीलाल व प्राइवेट पार्टियों द्वारा ही किया गया, बल्कि स्वयं दिल्ली पुलिस ने भी समूची रैली की वीडियो फिल्म बनायी है।

रैली के विशाल और सफल होने की संभावना आरंभ से ही थी। कारण, रैली की कमान जाने-माने संगठन और देवीलाल के ज्येष्ठ पुत्र हरियाणा जनता दल अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला के हाथों में थी। पिता की प्रतिष्ठा और कद-काठी में इजाफे के अतिरिक्त उनका अपना राजनीतिक भविष्य भी काफी हद तक इसकी भव्य सफलता पर आश्रित था। नतीजतन योजना और उसके क्रियान्वयन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गयी। न ही जायज-नाजायज की बंदिशें ही लगायी गयीं। आलोचकों के अनुसार रैली के आयोजन में करोड़ों रुपए स्वाहा किये गये। तैयारी के एक माह के दौरान संपूर्ण हरियाणा सरकार और प्रशासन दोनों इसी शुभ कार्य को सरअंजाम देने में जुटे रहे। प्रसार-प्रचार कार्य सरकारी स्तर से भी युद्ध स्तर पर हुआ। दिल्ली पर खास धावा बोला गया, जहां की दीवारें पोस्टरों से पटी पड़ी थीं। २५ प्रमुख स्थलों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे। देवीलाल के संघर्षों, उपलब्धियों के गुणगान से युक्त जैन स्टूडियो द्वारा निर्मित एक घंटे की वीडियो फिल्म नगर-नगर, गांव-गांव दिखायी गयी।

भीड़ जुटाने का काम हरियाणा के मंत्रियों-विधायकों के सिरमाथे रहा। अन्य सुविधाएं जुटाने में राज्य सरकार के चार प्रमुख विभागों ने महती भूमिका निभायी। बकौल कांग्रेस में नवप्रविष्ट रघु यादव, "पुलिस विभाग ने यदि ९००० से अधिक ट्रकों, मिनी बसों का जबरन बंदोबस्त किया, तो नागरिक आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल डीजल का। राजस्व विभाग से जुड़े पटवारियों, गिरदावरों की सुनिश्चित तादाद में लोगों को बटोरकर लाने की ड्यूटी लगायी गयी।" अपेक्षित अपार जनसमूह को नियंत्रित करने और आशंकित 'कांग्रेसी गुंडागर्दी' से निपटने के लिए १० हजार हरी वर्दीवाले वालेंटियरों की फौज को रेवाड़ी के पास बावल में ट्रेनिंग दी गयी, जिसका रैली को हादसारहित निपटाने में विशेष योगदान रहा।

विवाद: रैली की सफलता यदि संदेह से परे रही, तो उद्देश्य संदेह के घेरे में रहे। जन्मदिवस समारोह को, वह भी गृह और राज्य के बाहर राष्ट्र की राजधानी में आयोजित करने को, पक्ष-विपक्ष दोनों ने ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की राज्य के बाहर लांघती महत्वाकांक्षाओं का ही द्योतक माना। विशेषकर इसलिए कि नाम के वास्ते राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष रामाराव को समारोह का अध्यक्ष तो बनाया गया था, लेकिन स्वयं जनता दल तक प्रारंभ में इससे जुड़ा न था। जोड़ने का निर्णय पार्टी अध्यक्ष वीपी सिंह ने अंतिम क्षणों में ही किया। इसमें भी खानापूरी अधिक हुई वास्तविक काम कम।

उद्देश्य संबंधी संदेहों का प्रमुख कारण प्रसार-प्रचार के दौरान देवीलाल को 'युग-पुरुष', 'विपक्षी एकता का प्रतीक' तथा 'भावी राजनीति का जनक' आदि के रूप में प्रचारित किया जाता रहा। आम धारणा यही बनी कि दिल्ली की गद्दी पर अपना हक जतलाने की मशा के अतिरिक्त उस पर अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही बिठाने की यह परोक्ष घोषणा थी। अहं के तुष्टीकरण के चलते १९७८ में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित विशाल रैली से होड़ की नीयत भी किसी से छिपी न रह सकी। विडंबना ही है कि इसका स्मरण रैली के आरंभ में यदि चौधरी चरण सिंह के वारिस और जनता दल महासचिव अजीत सिंह ने देवीलाल को किसान नेता चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक अखाड़े का सबसे मजबूत पहलवान कहकर दिलाया, तो अंत में ओमप्रकाश चौटाला ने यह कहकर याद किया कि "२३ दिसंबर, १९७८ को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर की गयी रैली ने तब तक मानी जाने वाली सबसे बड़ी माओ-त्से-तुंग की रैली का रिकार्ड तोड़ दिया था। देवीलाल के जन्मदिन की इस रैली ने खुद चरण सिंह की रैली का बनाया रिकार्ड तोड़ दिया है।" यह एक प्रकार से होड़ की आत्म स्वीकृति है। जानकार लोगों ने रैली के पीछे जाट राजनीति पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास भी देखा। वह भी वर्तमान से अधिक भविष्य में। क्योंकि देवीलाल तो उम्र और अनुभव के लिहाज से इस वर्गविशेष के वर्तमान वरिष्ठतम नेता सर्वस्वीकृत हो भी जायें, तो भी भविष्य में लड़ाई अजीत सिंह, चौटाला अथवा रंजीत सिंह के मध्य होनी अवश्यंभावी है।

वर्तमान रैली चरण सिंह की रैली से बड़ी

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

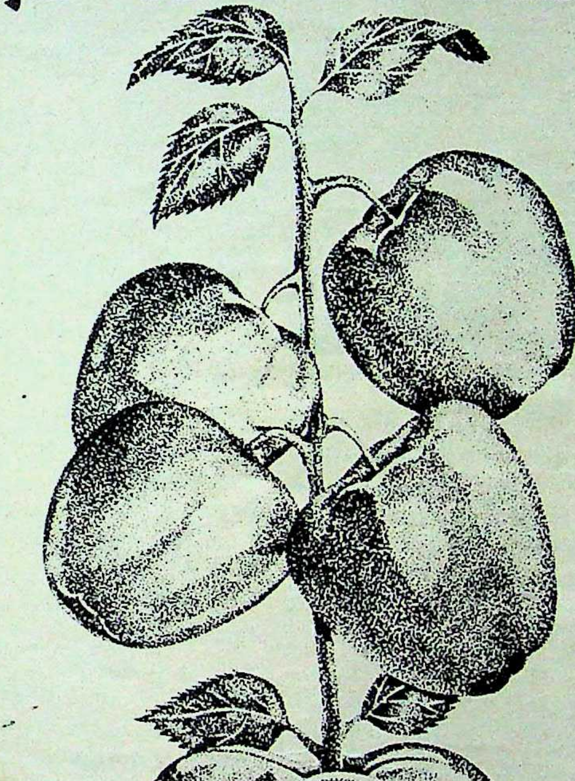

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टावर, कफ़ परेड, कोलाबा, बम्बई 400 005.

Sobhagya-B/89 HN

समर्थन का स्वागत: जनसमुदाय का अभिवादन करते हुए देवीलाल और चंद्रशेखर छाया: एस पाल

थी या छोटी (छोटी बतानेवालों की कमी नहीं), विवाद का विषय हो सकता है, किंतु इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं कि व्यक्तिविशेष (देवीलाल) का वर्चस्व स्थापित करने की मंशा से प्रेरित यह रैली अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों और अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर का संकेत भी दे गयी। शरद यादव के अनुसार, "रैली जनता दल और विरोध पक्ष की एकता का समरस भव्य दर्शन था। साथ ही वर्तमान सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगली कड़ी भी। जिस प्रकार कांग्रेस ने रैली पर हमला किया है, उससे उसके टूटते मनोबल और चिंता का ही खुलासा हुआ है।"

एकता की सूचक: गौरतलब है कि मंच पर माकपा को छोड़ अन्य सभी विपक्षी दलों की मौजूदगी विपक्षी एकजुटता पर समय-समय पर लगते प्रश्नचिह्न को हटाने में काफी हद तक सफल हुई। यह दीगर बात है कि कई पक्षों का शीर्ष नेतृत्व अनुपस्थित रहा। विपक्ष के अन्य चारों मुख्यमंत्रियों—ज्योति बसु, करुणानिधि, प्रफुल्ल महंत और ईके नयनार की उपस्थिति रैली में निश्चित ही और चार चांद लगाती। मंच से एक के बाद एक वक्ता द्वारा एकजुटता का उल्लेख और आगामी चुनाव में एक के विरुद्ध एक प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है। इस परिदृश्य में भाजपा नेता अटलबिहारी वाजपेयी का यह कथन कि यदि कोई तीसरा उम्मीदवार खड़ा हो, तो उसे अनदेखा किया जाये, विशेष महत्वपूर्ण है।

माकपा की गैरमौजूदगी गौरतलब रही, तो भाजपा की मौजूदगी उल्लेखनीय। यद्यपि आधिकारिक तौर पर माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत की आकस्मिक बीमारी को माकपा की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए उनकी शुभकामनाओं के संदेश को मंच से पढ़कर लीपापोती का प्रयास किया गया, किंतु जानकार सूत्रों के अनुसार मूल कारण उस भाजपा की उपस्थिति रही, जिस पर संप्रदायवाद का ठप्पा लगा माकपा न सिर्फ उसके साथ एक मंच पर न आने का संकल्प ही दोहराती रही है, बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों को भी दामन बचाने की राय देती रही है। इसके विपरीत रैली को हरियाणा में देवीलाल के साथ साझा सरकार चलानेवाली भाजपा ने कितना महत्व दिया, यह इस बात से उजागर हुआ कि बंबई में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़, दो नेताओं—वाजपेयी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया—ने इसमें भाग लिया। बदले में संयोजकों ने दोनों ही नेताओं को रैली संबोधित करने की प्रतिष्ठा प्रदान की। यह भी स्पष्ट हुआ कि वामपंथ की हाल की दबाव की राजनीति के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा ने हिंदीभाषी क्षेत्रों में भाजपा से चुनावी तालमेल का मन बना लिया है।

बड़े 'दादा' माकपा की गैरहाजिरी में छोटे भाई भाकपा की शिरकत और भी दिलचस्प रही। यह सत्य है कि आजादी की लड़ाई के दौरान भाकपा सचिव एम० फारूकी चौधरी देवीलाल के साथ न सिर्फ जेल में इकट्ठे ही रहे थे, बल्कि उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। किंतु भाकपा जैसी अनुशासित पार्टी में मात्र व्यक्तिगत संबंधों का महत्व नहीं होता, इसे फारूकी ने भी 'माया' से बातचीत में स्वीकारा। अत: रैली में फारूकी की मौजूदगी और उनका संबोधन सीटों के तालमेल और जनता दल—भाजपा संबंधों के बारे में माकपा की अपेक्षा भाकपा के अधिक लचीले और व्यावहारिक दृष्टिकोण का द्योतक है।

शीर्ष स्तर पर नेतृत्व को लेकर यदि कुछ संदेहों का बीजारोपण हुआ, तो निचले स्तर पर नेताओं की श्रेणियां बनती दिखायी दीं। जनता दल में अब तक सुर्खियों में रहे अनेक नेताओं—शरद यादव, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां, बीजू पटनायक, विद्याचरण शुक्ल आदि को रैली को संबोधित न करने देने को कुछ ने यदि चौटाला द्वारा उनको उनकी औकात जताने का प्रयास माना, तो कुछ ने दल में बढ़ती गुटबंदी का प्रतीक। उप्र जनता दल अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को संयोजक बनाया जाना एक ओर ओमप्रकाश चौटाला से उनके बढ़ते संबंधों का द्योतक रहा, तो दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजनीति में उनके धमाकेपूर्ण प्रवेश का। ज्ञात रहे, दिल्ली से लगे उप्र से जन, धन और संसाधन जुटाने का भार मुलायम सिंह के कंधों पर ही था। मुलायम सिंह के इस बढ़ावे के पीछे यह आम धारणा बनी कि देवीलाल गुट अजीत सिंह की घेरेबंदी में प्राणपण से जुटा है। दूसरी ओर, रैली की सफलता से चौटाला-समर्थकों का यह विश्वास बढ़ा है कि इसने उनके नेता को उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा सिंहासन के और नजदीक ला दिया है।

राजधानी पर मुख्यत: हरियाणा द्वारा धावा बोले जाने का एक लाभ सीधे-सीधे उस हरियाणा सरकार के खाते में भी गया, जिसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से आक्रामक तेवर अपना नये मोर्चे खोल लिये थे। पर्यवेक्षकों के अनुसार वर्तमान रैली और जनसमर्थन के कारण केंद्र अगला कोई भी कदम उठाने के पूर्व चार बार अवश्य सोचेगा। रैलियों के दिनोदिन बढ़ते आयोजन और महत्व के चलते दिल्ली दरबार पर सीधा हमला बोलने के लिए इस प्रकार की विपक्षी रैली सर्वथा आवश्यक और अपेक्षित थी। सच तो यह है कि इस प्रकार की दो-चार और रैलियां करने में यदि विपक्ष सफल हो जाता है, तो कांग्रेस का मनोबल गिरेगा। इस रैली से देवीलाल की छवि निखरी है और उनके हाथ मजबूत हुए हैं। किंतु विपक्षी हौसलों को बुलंद करने और उसको लामबंद करने के उनके अथक प्रयासों को भी नजरअंदाज करना अनुचित होगा। न्याययुद्ध के दौरान देवीलाल के जींद में आयोजित 'समस्त हरियाणा सम्मेलन' ने हरियाणा में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। आश्चर्य न होगा यदि २५ सितंबर की वोट क्लब रैली देश की राजनीति में परिवर्तन की दिशा में यही इतिहास दोहराये।

—रंजना कक्कड़

त संबंधों
'माया' में
रूकी की
तालमेल
बारे में
चीले और

यदि कुछ
स्तर पर
जनता दल
ओं—शरद
खां, बीजू
रैली को
द चौटाला
का प्रयास
का प्रतीक।
यादव को
ओमप्रकाश
क रहा, तो
धमाकेपूर्ण
से जन, धन
म सिंह के
बढ़ावे के
ीलाल गुट
से जुटा है।
चौटाला-
इसने उनके
हरियाणा
है।
ाणा द्वारा
-सीधे उस
या, जिसके
दिनों में
न लिये थे।
रैली और
ई भी कदम
। रैलियों के
व के चलते
नने के लिए
वश्यक और
कार की दो-
सफल हो
। इस रैली
उनके हाथ
ों को बुलंद
उनके अथक
चित होगा।
जींद में
म्मेलन' ने
मार्ग प्रशस्त
२५ सितंबर
में परिवर्तन
।
ना कक्कड़

Vi
GOVERNMENT
Q.C. MARK
U.P.
जैट
और
बोर-की
Vi®
सिर्फ़ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये!
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS

इंका मुख्यमंत्री

राजीव के चुनावी सिक्के कितने खरे, कितने खोटे ?

नारायण दत्त तिवारी

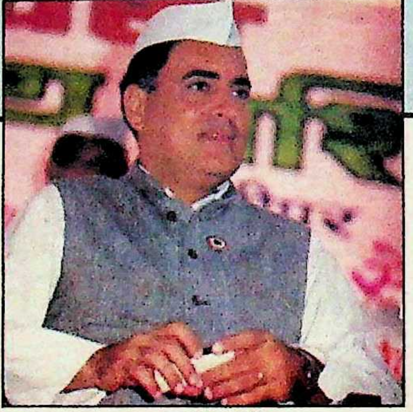

राजीव गांधी

सत्येंद्र नारायण सिंह

मोतीलाल वोरा

आगामी चुनाव में कांग्रेस के निर्णायक मोर्चे मुख्यमंत्रियों को संभालने हैं। इस समय उत्तर-मध्य भारत के प्रमुख राज्यों—बिहार, उप्र, मप्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान—में कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। इन राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की २९९ सीटें हैं। इन सीटों में से अधिकांश सीटें यदि जिता ली जाती हैं, तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनना सुनिश्चित है। लेकिन चुनाव में सक्षमता दिखाने के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त यह बात ज्यादा अहम है कि आलाकमान को इन मुख्यमंत्रियों की निष्ठा पर पूरा यकीन है या नहीं या वे चुनाव तक बने रहेंगे या नहीं !

यह सवाल इसलिए खड़ा होता है, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, जिसके बदले जाने की खबरें न उड़ी हों। व्यक्तिगत हैसियत से चुनाव जितानेवाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की निष्ठा पर तो उंगली तक उठायी गयी है। तिवारी का मामला इसलिए ज्यादा नाजुक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही यह तय करता है कि केंद्र में कौन सा दल राज करेगा। अतः कांग्रेस के प्रमुख सेनापतियों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि वे कांग्रेस की नैया पार लगा देंगे ? ब्यूरो रिपोर्टों के साथ अजय कुमार और पुनीत टंडन

चुनावी महाभारत में कांग्रेसी मुख्यमंत्री क्या पासा खेलेंगे, यह कहना अभी भी कठिन है। पर इतना जरूर तय है कि राजीव गांधी का भविष्य कांग्रेसी राजनीति के क्षितिज पर छाये 'सप्त ऋषियों' की चाल पर टिके रहने के लिए अभिशप्त है। क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई भी राजयोग उत्तर मध्य भारत के सात कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की 'ग्रह गणना' के बिना पूरा नहीं होता है। फिर चाहे इस सप्त ऋषि मंडल में ८५ लोकसभा सीटों को समेटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी हों या ५४ सीटों वाले बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह।

महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा से मोर्चा लेने का दम भरते शरद पवार, गुजरात में खुद अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों से मोर्चा लेते अमर सिंह चौधरी, राजस्थान में जोशी और पहाड़िया समर्थकों का हमला झेलते शिवचरण माथुर, मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा से लेकर उड़ीसा के जानकी वल्लभ पटनायक तक सात मुख्यमंत्रियों की इस सूची में शायद ही कोई हो जिस पर शंका-संदेह और असंतोष का ग्रहण न लगता रहा हो। नौबत यहां तक आ रही है कि प्रधानमंत्री या उनके अन्य सिपहसालारों को बारी-बारी से मुनादी करनी पड़ रही है कि फलां मुख्यमंत्री नहीं हटाये जायेंगे। १२ सितंबर को उप्र के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को स्थिर रखने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी को न हटाने की घोषणा कांग्रेस संगठन की लंबी बैठक के बाद दिल्ली में की गयी।

कीर्ति अंबानी की गिरफ्तारी के साथ ही

महाराष्ट्र के शक्तिशाली मुख्यमंत्री शरद पवार पर उमड़े शक और संदेह के बादल अभी छंट ही पाये थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद योजना मंत्री माधव सिंह सोलंकी के समर्थकों ने गुजरात में अमर सिंह चौधरी पर धावा बोल दिया। नतीजतन दिल्ली से भेजे गये केंद्रीय पर्यवेक्षक माखनलाल फोतेदार को अहमदाबाद से अपने कपड़े फड़वा कर वापस आना पड़ा। मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा और राजस्थान में शिवचरण माथुर के खिलाफ आये दिन पकनेवाली षड्यंत्र की खिचड़ी का मसला भी हर बार दिल्ली से ही भेजा जाता रहा है। बिहार में अपनी वफादारी की परीक्षा देते सत्येंद्र नारायण सिंह की हालत यह हो गयी है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के लिए इजाजत लेने के लिए हफ्तों दिल्ली में पड़ा रहना पड़ा।

जेबी पटनायक

अमर सिंह चौधरी

शरद पवार

शिवचरण माथुर

तीन सौ लोकसभा सीटों को समेटनेवाले इन सात राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा यदि उत्तर प्रदेश का है, तो शंका व संदेह के सबसे गहरे बादल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पर गहराये। यदि इसे संयोग न माना जाये, तो भी यह विचित्र सत्य है कि सबसे कम शंका-संदेह के बादल इन सात राज्यों में सबसे कम (२१) सीटोंवाले उड़ीसा के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर मंडराये। जबकि इन सात मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा खराब छवि पटनायक की ही रही है।

लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण कुरसी पर बैठे कांग्रेस के ये 'सात सिक्के' कितना चल पायेंगे? मुख्यमंत्रियों के रूप में उनकी छवि उनके राज्य में कांग्रेस को क्या फायदे और क्या नुकसान पहुंचायेगी? चुनाव संचालन की कांग्रेसी रणनीति में राज्य प्रशासन-पुलिस-लाठी और धन शक्ति के प्रयोग की इनमें किसकी क्या विशिष्टताएं हैं? जैसे तमाम सवालों पर जहां अभी इन सात मुख्यमंत्रियों को खरा उतरना होगा, वहीं दूसरी तरफ यह 'यक्ष प्रश्न' भी कायम है कि क्या चुनाव आते-आते खुद राजीव गांधी ही अपने इन 'चुनावी सिक्कों' को निष्ठा और वफादारी की कसौटी पर घिस-घिसकर 'कांतिहीन' तो नहीं कर देंगे। इनमें से किसी भी मुख्यमंत्री के जरा सा भी स्थापित होते ही खुद कांग्रेसियों द्वारा उसके खिलाफ आरोपों की भरमार शुरू कर देना, असंतुष्ट गतिविधियों को दिल्ली से संरक्षण मिलना शुरू हो जाना, क्या प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द बैठे सलाहकारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता का नतीजा भर है या यह सब कुछ खुद राजीव गांधी के अपने असुरक्षाबोध के चलते अपनायी, सोची-समझी केंद्रीय रणनीति का हिस्सा है? इसका निश्चित जवाब मिलना संभव नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे द्वारा फैलायी जा रही इस अफवाह पर ज्यादा यकीन किया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट मौजूद है जो जानबूझकर राजीव गांधी को कमजोर करने के लिए एक के बाद एक गड़बड़ियां खड़ी कर रहा है और आखिरी वक्त में 'लोग' अपने साथियों को साथ लेकर कांग्रेस से बाहर निकल कर विपक्ष से आ मिलेंगे।

यदि दूर की इस 'कौड़ी' को सही मान भी लिया जाये, तो आखिर एक-के-बाद-एक इन राज्यों में उथल-पुथल मचाती, शंकाएं फैलाती 'अदृश्य शक्ति' कौन है? क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त सत्ता के गलियारों में उड़ती अफवाह की आंधी में कमलापति त्रिपाठी से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक, अर्जुन सिंह से लेकर सत्येंद्र नारायण सिंह तक, बूटा सिंह से लेकर भजनलाल तक और धवन से लेकर फोतेदार तक शायद ही कोई बचा हो, जिसके खिलाफ शक और संशय की अदृश्य उंगलियां न उठी हों। इस हालत में मुख्यमंत्रियों के ऊपर मंडरानेवाले बादलों को क्या उनकी निष्ठा और वफादारी की अतिरिक्त परीक्षा भर माना जाये?

निर्णायक तीन: कम-से-कम नारायण दत्त तिवारी, शरद पवार और कुछ हद तक सत्येंद्र नारायण सिंह के मामले में यह सही माना जा सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से ये तीन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले तीन स्थानों पर आते हैं। तिवारी को छोड़कर बाकी दोनों ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले एक दफे कांग्रेस को छोड़ कर राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में शक्तिशाली हैसियत में रह चुके हैं। उसमें भी शरद पवार तो सीधे-सीधे विपक्ष के सर्वसम्मत भावी मुख्यमंत्री पद से कुछ ही समय पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक अंकगणित में शरद पवार का यही दलबदल उनके और शक्तिशाली होने का कारण बन गया। "विपक्ष में सर्वाधिक शक्तिशाली होने के नाते वे लगभग सर्वमान्य नेता तो थे ही, कांग्रेस में आकर मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के भी नेता हो गये।" महाराष्ट्र के एक सांसद का 'माया' से कहना था।

यही वजह थी कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेसी मुख्यमंत्री शरद पवार से खुद कांग्रेसी विधायक यह मजाक करने लगे कि विरोधी दल नेता मृणाल गोरे तो आपके खिलाफ कोई आरोप लगायेंगी नहीं, हम ही कुछ सरकार के खिलाफ बोलें। आखिर सदन की कार्यवाही तो चलानी ही है। महाराष्ट्र विधानसभा में पवार को मिलने वाली लगभग 'वाक-ओवर' जैसी स्थिति का एक बड़ा कारण जहां पवार के पीछे खड़ी शक्तिशाली मराठा लाबी है, वहीं दूसरा कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण हलकों में चल रहे किसान आंदोलनों के साथ पवार द्वारा बिठाया गया अपना राजनीतिक तालमेल भी है। कांग्रेस में आने के साथ ही पवार अपने ऊपर भविष्य में आनेवाले खतरों की काट पहले से ही सोच-समझकर लाये थे और वही हुआ।

शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और शक्तिशाली होते देख दिल्ली दरबार का चिंतित होना स्वाभाविक था। आखिरकार तय हुआ कि महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले को और 'प्रोजेक्ट' कर शक्तिशाली बनाया जाये। एक लंबे अरसे से उपेक्षित पड़े अंतुले की अचानक दिल्ली में पूछ होने लगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से होने वाली मुलाकातों के बीच पड़ी अड़चनें अचानक दूर हो गयीं। पर दिल्ली के फैसले के बावजूद अंतुले का महाराष्ट्र में शक्तिशाली होने का मार्ग अवरुद्ध रहा। इससे दिल्ली के कान खड़े हुए। लेकिन दिल्ली कर भी क्या सकती थी। पवार की राजनीति जाननेवालों के लिए कारण एकदम साफ था। दरअसल, पवार पहले ही अंतुले के खतरे को देखते हुए उनकी काट के रूप में महाराष्ट्र के एक शक्तिशाली मुसलमान नेता डा० इसहाक जिम खानवाला को साथ लेकर आये थे। डा० जिम खानवाला पूरे महाराष्ट्र भर में फैले अपने इस्लामी मदरसों, शैक्षणिक संस्थाओं के व्यापक जाल के जरिये महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण

दोनों ही क्षेत्रों के मुसलमानों के बीच गुपचुप गहरी पैठ बना चुके थे। मंत्रिमंडल में शरद पवार के दायें हाथ के रूप में स्थापित होकर और शहरी विकास जैसे महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ ही वक्फ मंत्रालय लेकर डा० जिम खानवाला ने यह राजनीतिक हैसियत बना ली थी कि अंतुले के लिए दिल्ली की पूरी मदद के बावजूद अपनी जमीन तलाशना मुश्किल हो रहा था।

शरद पवार के समानांतर अंतुले को स्थापित करने की मुहिम की असफलता के बाद अचानक खुद कांग्रेस की ही तरफ से शरद पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप उछलने शुरू हुए। पहले ये आरोप पार्टी के अंदर ही रहे। फिर अखबारों में भूमि घोटालों से लेकर तमाम अन्य आरोपों की शक्ल में उछलने लगे। इसी के साथ पवार को हटाने की चर्चा दिल्ली में तेज हुई और राज्य में न्यूनतम असंतोष के बावजूद पवार अब गये तब गये की नौबत आ गयी।

मुहिम की काट : जहां एक तरफ दिल्ली में पवार को हटाने की चर्चा ने जोर मारा, वही बंबई में पवार की पुलिस ने राजीव गांधी के प्रबल शत्रु उद्योगपति नस्ली वाडिया की हत्या के षड्यंत्र के आठ महीने पुराने आरोप के आधार पर दिल्ली दरबार के खासम-खास उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के रिलायंस उद्योग में जन-संपर्क विभाग के महाप्रबंधक कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार कर बाजी पलट दी। शुरू के दो दिन पवार के हटाये जाने की खबर और तेज हुई, फिर तीन दिन सन्नाटे और दिल्ली-बंबई के बीच यात्राओं-लंबी वार्ताओं का रहा। उसके बाद नतीजा यह था कि राजीव गांधी को खुद नागपुर जाकर पवार की सरकार को जनसभा में 'सर्टीफिकेट' देना पड़ा कि पवार को हटाये जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद पवार पर मंडराये खतरे के बादल भले ही चुनाव तक के लिए समाप्त हो गये, पर वे संदिग्ध नहीं रहे, यह कहना कठिन है।

इस हालत में पवार किस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस को अगला चुनाव लड़वायेंगे, इस पर दिल्ली में अभी भी मतभेद है। पर मोटे तौर पर दोनों ही पक्ष (शरद पवार पर शक करने और शक न करनेवाले) इससे सहमत हैं कि इस पूरे घटनाक्रम और अपनी कार्यशैली से शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी एक ज्यादा मजबूत और क्षेत्रीय स्वाभिमान को बल देनेवाली छवि बनायी है, जिसका कांग्रेस को ही अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

बिहार : वहीं बिहार में संकट का कारण उलटा है। शरद पवार और नारायण दत्त तिवारी की तरह अपने-अपने राज्य में एक विकल्पहीन स्थिति बना लेने के बजाय सत्येंद्र नारायण सिंह ने राज्य में एक साथ अनेक विकल्पों को पैदा कर लिया है। फिर चाहे वे जगन्नाथ मिश्र हों, भागवत झा आजाद हों, बिंदेश्वरी दुबे हों या तारिक अनवर। इसके अतिरिक्त दिल्ली में बैठे सीताराम केसरी का भी 'राज्य प्रेम' रह-रह कर जोर मारता रहा है। यह हालत एक हद तक केंद्र के लिए एक आदर्श स्थिति है। जहां लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लगभग समान शक्ति के नेता एक दूसरे की कुर्ता-खींच दौड़ में शामिल हों, वहां मुख्यमंत्री केंद्र की कृपा का ज्यादा आकांक्षी होता है। पर चुनाव के मौके पर कांग्रेस को इस खींचतान की कीमत देनी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद बिहार के एक मंत्री का 'माया' से कहना था, "इसके दो पहलू हैं समस्या उस दिन तक घनघोर रहेगी, जब तक पार्टी के टिकट नहीं बांटे जाते। हर लाबी अपने-अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए जान तक का जोर लगायेगी। पर एक बार जब टिकट बंट गये, तो कांग्रेस के पास वोट इकट्ठे करने के लिए राज्य में लगभग हर जाति के एक नहीं एक साथ कई बड़े-बड़े कद के नेता मौजूद होंगे।"

पर दिल्ली में सत्येंद्र नारायण सिंह की विरोधी लाबी का तर्क इसका उलटा है। उसका मानना है, "विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने ठाकुर वोट तो सत्येंद्र नारायण सिंह कांग्रेस के लिए खींच कर लाने में असफल रहेंगे ही, ठाकुर मुख्यमंत्री होने के नाते ब्राह्मण और हरिजन भी कांग्रेस से किनारा कर लेंगे।"

तिवारी के प्रयत्नों को धक्का : बदायूं में हिंसा

शक नहीं, पर संकट : पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में असंतोष का सामना कर रहे मुख्यमंत्रियों की स्थिति उलटी है। यहां शक और संदेह की दूर तक कोई संभावना न नजर आती है और न ही उसका दूर तक कोई आधार हो सकता है। मोतीलाल वोरा, शिवचरण माथुर और अमर सिंह चौधरी के लिए फिलहाल शायद ही कोई सपने में भी सोच सके कि वे कभी शरद पवार की तरह सीधे दिल्ली से अपनी शर्तों पर समझौते की बात करेंगे या राज्य में नारायण दत्त तिवारी की तरह निर्विकल्प हो जायेंगे। उलटे इन तीनों मुख्यमंत्रियों को उन महारथियों से जूझना पड़ रहा है, जिन पर उलटे 'दिल्ली' को शक रहा है फिर चाहे वे मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह हों, राजस्थान में हरिदेव जोशी हों या गुजरात में माधव सिंह सोलंकी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इन तीनों में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने अपमान को भूला हो। सोलंकी और जोशी तो फिर भी मंत्री और राज्यपाल का पद पाकर संतोष कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जैसे प्रभावशाली नेता की उपेक्षा महंगी पड़ सकती है।

मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा का संकट बुनियादी रूप से खुद राजीव गांधी के संकट की प्रतिच्छाया है। चुरहट लाटरी कांड में अर्जुन सिंह को पूरी तरह बदनाम होने देने व मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी आलाकमान और सलाहकार अभी तक मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के 'आतंक' से उबर नहीं पाये हैं। 'इस हालत में चुनाव में अर्जुन सिंह अंदर-ही-अंदर क्या गुल खिलायेंगे' के शक के बावजूद सिंह को चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। २८ सितंबर को राजीव गांधी ने अपनी मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान सिंह को साथ ले जाकर जहां इसकी पुष्टि की है, वहीं इससे वोरा के खिलाफ असंतुष्ट गतिविधियों को एक बार फिर हवा मिल गयी है। यह बात दूसरी है कि इसके बावजूद न तो वोरा के आत्मविश्वास में कोई कमी आयी है और न ही उनकी दिल्ली यात्राओं में कोई कमी हुई है। "मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, हमें भारी सफलता हासिल होगी," 'माया' से वोरा का कहना था।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस का असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। यह विडंबना ही है कि भाजपा को जिस चुरहट लाटरी कांड में अर्जुन सिंह से ज्यादा कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करने का मौका मिला है, उसमें ऐसा हलफनामा देने का श्रेय स्वयं वोरा को ही है, जिसके कारण फैसला अर्जुन सिंह के खिलाफ गया। ऐसी स्थिति में देखना है कि वोरा अपनी सज्जन और अपेक्षाकृत ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि ओढ़कर कांग्रेस पर लगनेवाले भ्रष्टाचार के आरोपों को कितना बेअसर कर पाते हैं। अर्जुन सिंह जैसे तेजतर्रार मुख्यमंत्री की तरह वे राज्य प्रशासन व साधनों को 'पार्टी के हित में' इस्तेमाल करने के लिए जुटा पायेंगे, इस पर बहुतों को शक है। फिर अस्थिरता की तलवार तो उन पर लटकती रहेगी ही।

राजस्थान की जातीय राजनीतिक बिसात पर शिवचरण माथुर के लिए चुनाव में कुछ करने के लिए नहीं है। पिछले चुनावों के दौरान भरतपुर के पास डींग के राजा मानसिंह को गोली से उड़वा देने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटे माथुर फिर मुख्यमंत्री के पद पर दुबारा तभी पहुंच पाये, जब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

गुजरात में बने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी को यह गद्दी तब मिली, जब गुजरात के एकछत्र नेता बनने के मद में माधव सिंह सोलंकी ने पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा करके पूरे राज्य को दंगों की आग में झोंक दिया। चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि प्रदेश में छोटे-छोटे समूहों में

बिखरे आदिवासी-हरिजन वोट जहां पूरी तरह से कांग्रेस की मुट्ठी में आ गये हैं, वहीं दूसरी तरफ चौधरी के खिलाफ सोलंकी खेमे द्वारा चलायी जा रही मुहिम ने प्रदेश कांग्रेस के संगठन को बुरी तरह छिन्न-भिन्न कर दिया है। प्रदेश के इस झगड़े ने तद्र और भी तूल पकड़ लिया, जब राज्य के इस झगड़े ने फोतेदार बनाम धवन के झगड़े की शक्ल ले ली। चौधरी को जहां गुजरात के लिए बनायी गयी समन्वय समिति के संयोजक फोतेदार का समर्थन प्राप्त था, वहीं सोलंकी धवन से आशीर्वाद हासिल करने में सफल हो गये।

दोनों के झगड़े में कभी इंका का गढ़ माने जानेवाले गुजरात का सत्यानाश होता देख राजीव गांधी ने पूरा मामला केंद्रीय यातायात राज्य मंत्री राजेश पायलट के हवाले किया। पर तब तक खासी देर हो चुकी थी। फिलहाल दोनों ही पक्षों को समझा-बुझाकर यथास्थिति कायम रखने और चौधरी को आगे सरकार चलाते रहने का आदेश देकर मामला शांत कराया गया। पर इससे होनेवाला नुकसान तो पहले ही कांग्रेस को हो चुका था।

भविष्यनियंता प्रदेश : यद्यपि राजीव गांधी के सार्वजनिक बयान के बाद यह माना जा सकता है कि नारायण दत्त तिवारी की निर्मल निष्ठा पर संदेह की जो काई चढ़ गयी थी, वह छितरा गयी है (देखिए संलग्न कथा)। लेकिन तिवारी की संभ्रांत और तिकड़मरहित कार्यशैली की दुर्व्याख्याएं करके जिन लोगों ने असंदिग्ध तिवारी को संदिग्ध बनाया था, वे लोग तिवारी की चुनाव-रणनीति का सुचारु कार्यान्वयन होने देंगे—ऐसा नहीं लगता। प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन का तालमेल चुनाव में जीत का रास्ता हमवार कर सकता है, लेकिन यहां तो परस्पर-विरोधी धाराएं फूट रही हैं। प्रदेश इंका अध्यक्ष बलराम सिंह स्वयं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऊर्जा मंत्री नरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। टिकैत से समझौता कराने में नरेंद्र सिंह को दी गयी भूमिका को इसके ताजा उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। संगठन की मजबूती के संबंध में बलराम सिंह का दावा है, "मेरे पद-ग्रहण करने के बाद ३०० चुने हुए प्रतिनिधि और हजारों पूर्व विधायक, पदाधिकारी व प्रमुख विपक्षी कार्यकर्ता कांग्रेस में आये हैं। जिलों में १७० रैलियां आयोजित की गयीं। प्रत्येक में १० से २५ हजार तक लोगों ने भाग लिया। इससे संगठन में नयी चेतना आयी है।" लेकिन नरेंद्र सिंह संगठन की सशक्तता के प्रति आश्वस्त नहीं हैं, "संगठन द्वारा बूथ कमेटियां तक गठित करने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक ब्लाक स्तर तक की कमेटियों का गठन नहीं हो सका है।" इन परस्पर विरोधी धारणाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेसजन कितने एकजुट होकर चुनाव में लग सकेंगे। मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार हैं—सिंचाईमंत्री लोकपति त्रिपाठी। लखनऊ के मेयर के चुनाव और १५ सितंबर, १९८९ को कानपुर देहात में अमरहा पंप कैनाल योजना के उद्घाटन के समय लोकपति त्रिपाठी को जो महत्व दिया गया, उससे नगर विकास राज्यमंत्री श्रीनाथ सिंह बहुत खुश नहीं हैं। श्रीनाथ सिंह, त्रिपाठी के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। काबीना मंत्री और राज्य मंत्री के अधिकारों को लेकर भी मंत्रियों के गिले-शिकवे हैं। राज्यमंत्री शिवनाथ कुशवाहा इस बात से नाराज माने जाते हैं कि तिवारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे अधिकार अम्मार रिजवी को दे रखे हैं। 'दमदमी टकसाल' के नाम से चर्चित ७२ युवा विधायकों की शिकायत है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। गुटबाजी का आलम यह है कि इलाहाबाद में मेयर के चुनाव में अशोक वाजपेयी को जीतते हुए भी हरा दिया गया और अब वे अपनी जितनी राजनीतिक जड़ जमाने की कोशिश करते हैं, प्रदेश के मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय और कांग्रेस महासचिव केपी तिवारी उन्हें उखाड़ने की उतनी ही कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं, जिनसे लगता है कि सरकार और संगठन में गुटबाजी है जो चुनाव पर असर डालेगी।

> तिवारी को यदि दिल्ली ने चैन से काम करने दिया और संकट की घड़ी में इंका की गुटबाजी पर यदि वे अंकुश लगा पाये, तो अपनी शालीनता, स्वच्छता और विकास कार्यों के हथियार से वे विपक्ष का तगड़ा मुकाबला करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। शेष छह इंका मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वे ज्यादा खरे सिद्ध हो पायेंगे।

लेकिन तिवारी इन गुटबाजियों की खामियों को अपने विकास कार्यों के जरिये विभिन्न वर्गों को कांग्रेस के पक्ष में जुटा कर पूरा करने में लगे हैं। अपने संपर्कों से उन्होंने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से २५ अरब रुपए प्राप्त किये हैं। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के प्रभाव को धोने के लिए वे हरिजनों और निर्बल वर्गों के लिए धड़ाधड़ योजनाएं चला रहे हैं। लखनऊ में निर्माणाधीन अंबेदकर विश्वविद्यालय के लिए एक अरब रुपए की व्यवस्था करना, ३५ हजार मकान प्रदान करके और ढाई लाख और मकान बनाने की घोषणा करके तिवारी ने उपर्युक्त वर्गों को कांग्रेस की ओर लुभाया है।

अल्पसंख्यकों को लुभाने में भी तिवारी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। उर्दू अकादमी को भरपूर योगदान, पांच हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति और अब उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना इसी ओर बढ़ाये गये कदम हैं। अयोध्या के विवादास्पद धार्मिक स्थान को भी न्यायिक प्रक्रिया में डालकर वे यथास्थिति बनाये रखने की कोशिश में लगे हैं। यद्यपि बदायूं में हुए दंगे ने तिवारी के प्रयत्नों को ठेस पहुंचायी है, जिनमें दो दर्जन निरीह लोगों को सांप्रदायिक दरिंदों के हाथों जान गंवानी पड़ी हैं।

सरकारी खजाने पर ६५६ करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय भार को वहन कर प्रदेश के २३ लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन और तदर्थ शिक्षकों के नियमितकरण की मंजूरी देकर तिवारी ने शिक्षित मतदाताओं पर भी डोरे डाले हैं।

तिवारी की प्रशासकीय कार्यकुशलता भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी थाती है और इसका मतदाताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वे विकास कार्यों की पत्रावलियों को तुरंत निपटाते ही नहीं, उनका बड़ा सूक्ष्म परीक्षण भी करते हैं। परिवहन राज्यमंत्री प्रमोद तिवारी ने 'माया' को बताया, "तिवारीजी द्वारा पत्रावली पर जो टिप्पणी लिखी जाती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने टिप्पणी लिखने से पूर्व पत्रावली के एक-एक शब्द को पढ़ा है।" बड़ी बात यह भी है कि तिवारी जनपद के कार्यकर्ताओं को निजी तौर पर पहचानते हैं। इससे चुनाव में वे उनका ज्यादा उपयोग करने की स्थिति में हैं। प्रदेश के वन तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री जगदंबिका पाल कहते हैं, "राजीवजी के बाद तिवारीजी ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रदेश का भ्रमण कर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है। उनकी विकास योजनाओं से कांग्रेस की फिजा बन रही है।"

तिवारी उक्त सभी खूबियों-खामियों के साथ ऐसे ऐतिहासिक चुनाव की तैयारी में लगे हैं जो राजीव गांधी का ही नहीं, कांग्रेस के भविष्य का भी निर्णय करेगा। तिवारी पर सर्वाधिक दायित्व इस कारण भी है कि उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से यह तय करता है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। फिर वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर और अजीत सिंह जैसे विपक्षी नेता भी उत्तर प्रदेश के हैं और राजीव गांधी की तरह उक्त विपक्षी नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। तिवारी को यदि दिल्ली ने चैन से काम करने दिया और संकट की घड़ी में इंका की गुटबाजी पर यदि वे अंकुश लगा पाये, तो अपनी शालीनता, स्वच्छता और विकास कार्यों के हथियार से वे विपक्ष का तगड़ा मुकाबला करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। शेष छह इंका मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वे ज्यादा खरे सिद्ध हो पायेंगे।

'छाया: रामशंकर सिंह, राजेंद्र कुमार

आपको हटाने की खबरें झूठी हैं: राजीव गांधी के साथ नारायण दत्त तिवारी

छाया: मनमोहन शर्मा

राजीव गांधी तिवारी से क्या खफा थे?

मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं, केंद्र में राजीव गांधी के बाद सर्वोपरि स्थान पर भी रहे हैं। देश की राजनीति के निर्णायक प्रदेश में कांग्रेस को आगामी चुनाव में जिताने का हिमालयी दायित्व उन पर ही है। लेकिन इस नाजुक क्षण में पिछले दिनों यह नौबत क्यों आयी कि प्रधानमंत्री को भरी सभा में कहना पड़ा कि तिवारीजी को हटाने की जो खबरें विपक्षी उड़ा रहे हैं, वे निराधार हैं? क्या वास्तव में ये खबरें निराधार थीं या सिलसिलेवार कांग्रेसी खेमे में तिवारी के विरुद्ध मुहिम चलायी जा रही थी? जिन हालात के बाद राजीव गांधी ने तिवारी पर विश्वास व्यक्त किया है, क्या वे आगे चलकर तिवारी की चुनाव जिताने की क्षमता पर असर नहीं डालेंगे?

और यक्ष प्रश्न अनुत्तरित रहा!

न ही राजीव गांधी ने सीधे सवाल पूछने का साहस (राजनीतिक शब्दावली में 'बचपना') दिखाया और न ही व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुकी नारायण दत्त तिवारी की मुस्कराहट ने किसी जवाब की शक्ल ली। कुल मिला कर इस पेचीदा बिसात पर दोनों ही ओर से बिछी गोटें ज्यों-की-त्यों रहीं और चुनाव के ऐन वक्त पहले राजीव गांधी ने अपने भविष्य का सबसे बड़ा दांव नारायण दत्त तिवारी की बंद मुट्ठी पर लगा दिया। जहां उत्तर प्रदेश की कुल ८५ लोकसभा सीटों के साथ ही खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सीट और अगले चुनावों में कांग्रेस का भविष्य भी बहुत हद तक कैद है।

आठ से बारह सितंबर तक दिल्ली दरबार ने दिन रात इसी यक्ष-प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने की अथक कोशिश की थी। पर चार दिन की प्रतीक्षा के बाद कहीं जाकर ग्यारह सितंबर को देर रात डेढ़ बजे राजीव गांधी से हुई नारायण दत्त तिवारी की मुलाकात तक भी जब उत्तर नहीं निकल पाया, तो 'वेताल' को हमेशा की तरह फिर वापस बरगद के पेड़ पर लौटना ही था। जहां मे पिछले कई महीनों से दिल्ली दरबार के लगभग सभी महारथी उसे उतार कर लाने के 'विक्रमादित्य प्रयास' में जुटे हुए थे।

कांग्रेस के बरगद पर लटका 'संदेह' का वेताल आज भी ज्यों-का-त्यों झूल रहा है और उसे उतार कर ले जाने की शर्त बना 'यक्ष प्रश्न' अभी भी अनुत्तरित है। कुल मिला कर यह पहला मौका है जब इक्कीसवीं सदी की ओर दौड़ रहे राजीव गांधी और उनके सलाहकारों को पीछे मुड़ कर शताब्दियों पुरानी यक्ष प्रश्नावलियां, वेताल कथाएं और सैकड़ों सालों से कही सुनायी जा रही लोक कथाएं एक साथ याद आयी हों।

अचानक बयान : बारह सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अचानक बयान जारी कर आलाकमान का स्टैंड साफ किया। 'उत्तर प्रदेश मे नेतृत्व परिवर्तन नही होगा'—बयान जारी करनेवाले आजाद कांग्रेस के राष्ट्रींय महासचिव के रूप में जहां उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी हैं, तो वहीं तिवारी के प्रबल विरोधियों में माने जाते हैं। आजाद का कहना था, "श्री तिवारी को बदले जाने के बारे में उड़ायी गयी खबरें राजनीति से प्रेरित हैं।" वहीं वे उत्तर प्रदेश को यह प्रमाण पत्र देना भी नहीं भूले, "यह एक ऐसा प्रदेश है, जहां सरकार और संगठन में पूरी तरह तालमेल है। यह एक सुशासित राज्य है और पार्टी बिना किसी अड़चन के काम कर रही है।" उनका मानना था, "राज्य सरकार और पार्टी के सुचारु काम से चिढ़ कर कुछ विरोधी तत्व जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।"

यहां दो बातें साफ हैं एक—कि तिवारी को हटाये जाने की न केवल धुआंधार चर्चा थी, बल्कि यह चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आलाकमान को इसका खंडन करने के लिए बयान जारी करवाना पड़ा। दूसरे, यह बयान तभी जारी हुआ जब लंबी दुविधा-अटकलों से भरे इंतजार के बाद ग्यारह सितंबर की रात आखिरकार तिवारी की राजीव गांधी से मुलाकात हो गयी। अकेले में हुई इस मुलाकात का पूरा का पूरा ब्यौरा जानना किसी भी तीसरे के लिए मुश्किल है। अगले पूरे दिन राजधानी में वरिष्ठ इंका नेताओं से लेकर दिग्गज राजनीतिक समीक्षक और संवाददाता इस बहस में उलझे रहे कि क्या राजीव गांधी और नारायण दत्त तिवारी के बीच कोई समझौता हुआ है? क्या तिवारी ने आलाकमान के आगे पूर्ण समर्पण कर दिया? या आखिरकार आलाकमान को उत्तर प्रदेश के इस 'नारायण' के सामने घुटने टेकने पड़े?

पर यह सचाई है कि आजाद के बयान भर से काम नहीं चला। और अनुत्तरित यक्ष प्रश्न दिल्ली दरबार के आसमान पर घुमड़ता रहा। पंद्रह सितंबर को खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान अपने मुंह से घोषणा करनी पड़ी कि तिवारी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। गांधी ने तिवारी के प्रशासन और उनकी राजनीतिक सूझबूझ की भूरि-भूरि प्रशंसा की और साफ किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तिवारी ही लड़वायेंगे। उस रात दिल्ली दरबार में तमाम दरबारियों को एक साथ एक ही कथा याद आ रही थी:

"...दुश्मन की सेनाओं को आता देख राजा ने अपनी जान एक मैना में रख चांदी का पिजड़ा राजपुरोहित को सौंप दिया। बूढ़ा पुरोहित मैना को पिजड़े में संभाले अकेला दूर लिये जा रहा है, जहां बैरी दस्यु हवाएं मैना को छू तक न सकें।

दरबारियों को शक है कि कहीं पुरोहित की ही नीयत न खराब हो जाये और वह खुद ही मैना का गला दबोच कर पूरे राज वैभव का स्वामी न बन जाये। वेताल सवाल पूछता है कि शंकालु राजा ने आखिर 'मैना' उस बूढ़े ब्राह्मण के हाथों क्यों सौंप दी? क्या वह उस मैना को सुरक्षित रख पायेगा? या राजा पर आये संकट के क्षणों में खुद ही मैना का गला दबा देगा? राजदरबारियों का राजपुरोहित पर शक कितना सही है? वेताल के इन यक्ष प्रश्नों का दिल्ली दरबार के पास आज भी कोई जवाब नहीं है।..."

शक-शुबहा : जवाब, नारायण दत्त तिवारी का भी कोई नहीं है। इस बात को राजीव गांधी खुद और उनके सलाहकार अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आखिर क्या वजह थी कि दिल्ली दरबार का लगभग हर सिपहसालार बेहद मृदुभाषी और विनम्र तिवारी का विरोधी हो गया? जनता काल के दुर्दिनों में भी श्रीमती गांधी के साथ साये की तरह जुड़े रहने वाले 'वफादार तिवारी' के शुभ्र दामन पर शंका के स्याह धब्बे मंडराने लगे। भारतीय राजनीति में पहली दफा यह मिसाल कायम हुई कि दूरदर्शन जैसे शक्तिशाली सरकारी मीडिया पर किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछ कर यह सफायी लेनी पड़ी हो कि—"क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं?" राष्ट्रीय चैनल पर देश के करोड़ों दर्शकों के सामने यह 'कमिट' करवाने की जरूरत पड़ी हो कि "मेरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसके लिए राजीव गांधी ही एकमात्र योग्य नेता हैं और वही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और आगे भी संभालेंगे।"

शीला दीक्षित

शीला दीक्षित ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत किया। पर उसके बाद ही नारायण दत्त तिवारी से हुई मुलाकात में उनका सारा गुबार बाहर था।

क्या तिवारी पर घुमड़े संदेह के बादल, दिल्ली दरबार के सिपहसालार-सलाहकारों की तिवारी से नाराजगी और प्रधानमंत्री निवास से लेकर दूरदर्शन तक पर हुई इन कसरतों का कारण तिवारी की प्रशंसा में दिया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह का बयान भर है? सिंह ने तिवारी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त कांग्रेसी नेता बताया था। क्या राजीव गांधी और उनके सलाहकार इतने नासमझ और असुरक्षा भाव से ग्रस्त हैं कि विपक्ष के एक नेता के सिर्फ एक प्रशंसात्मक बयान के चलते ठीक चुनाव के पहले नारायण दत्त तिवारी जैसे विश्वसनीय और शक्तिशाली नेता को उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में उखाड़ने में लग जायें? क्या यही कारण था कि पचास साल तक आडंबररहित शैली में विनम्रता की राजनीति करनेवाले नारायण दत्त तिवारी के बचाव में देश के तमाम अखबारों—पत्र पत्रिकाओं में उनकी घनघोर प्रशंसा, संपादकीयों, अग्रलेखों और आवरण कथाओं की झड़ी लग गयी? क्या नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूरी बन गये हैं? इस प्रश्न ने आलाकमान के कान तब खड़े किये, जब तिवारी की बदली हुई राजनीतिक कार्यशैली ने दरबार के हर सिपहसालार को पसोपेश में डालना शुरू कर दिया। फिर वे चाहे उत्तर प्रदेश के मामलों के इंचार्ज राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद हों या प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी निर्विवाद और गुटविहीन छवि के चलते प्रभावशील बनी शीला दीक्षित हों। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री दिनेश सिंह से लेकर रक्षामंत्री केसी पंत तक महारथियों की एक पूरी की पूरी जमात अपने अलग-अलग कारणों से वैसे ही तिवारी के खिलाफ मोर्चा लगाये बैठी थी।

गोपनीय रणनीति : इस बीच उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्म पर उगली रख दी। इस साल की शरुआत में ही चुनावी तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री द्वारा बुलायी गयी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी हित में कुछ फैसले लिये गये थे, जिन्हें चुनावी रणनीति के चलते गोपनीय रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह था कि राज्यों के लिए नियुक्त समन्वय समितियां यह देखेंगी कि हर कांग्रेसी सांसद को चुनाव वर्ष में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां तक संभव हो मनपसंद जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी दिये जायें। समन्वय समितियों की जिम्मेदारी थी कि वे इंकाई सांसदों से उनके मनपसंद अधिकारियों की सूची लेकर मुख्यमंत्रियों से तबादले करवायें, ताकि चुनाव के वर्ष और चुनाव के दौरान इंकाई सांसदों को अपने क्षेत्र में 'असुविधा' का सामना न करना पड़े।

प्रधानमंत्री से तिवारी की मुलाकात के पहले बूटा सिंह और तिवारी के बीच गुपचुप दो लंबी वार्ताएं हो चुकी थीं जिनका ब्यौरा लेकर सिंह प्रधानमंत्री से मिल चुके थे।

बूटा सिंह

मोटे अनुमान के तहत देश में सिर्फ चालीस से पचास फीसदी इंका सांसद ऐसे थे, जिन्हें अपने जिलों में बड़ी फेरबदल की जरूरत पड़ रही थी। बाकी कुछ अपने यहां तैनात अधिकारियों से अपना तालमेल बिठा चुके थे, तो कुछ अपनी इच्छा के अधिकारी पहले ही लाने में कामयाब हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में जहां इच्छानुसार अधिकारियों का अपने क्षेत्र में तबादला करवानेवाले सांसदों का प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले कुछ ज्यादा था, तो वहीं अधिकारियों की सूची जिलाधिकारी से लेकर दरोगा और जूनियर इंजीनियर और परगना विकास अधिकारी तक फैली हुई थी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगभग चार मौके तो ऐसे आये, जब 'दिल्ली' ने खुद तिवारी को निर्देश दिये कि वे इस मामले को देख कर सांसदों की इच्छानुसार राज्य में तबादले कर दें। तिवारी ने हर बात पूरी विनम्रता से सुनी। 'ठीक है' की स्वीकृति भरी, पर तबादले नहीं हुए। आखिरी बार इस बाबत दिल्ली में फिर जब एक उच्चस्तरीय बैठक में तिवारी से यह कहा गया, तो पूरी विनम्रता से उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में बात खतम कर दी, "अब चुनाव के वक्त ज्यादा उलटफेर करना ठीक नहीं है।" "पर यह फैसला तो आज से नौ महीने पहले हुआ था," खिसियाये हुए दिल्ली दरबार के नुमाइंदे ने फिर जोर मारा। तिवारी फिर पूरी मृदुता से भर कर धीमे से बोले— 'हूं' और बात खतम हो गयी। "अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उनका पूरा व्यक्तित्व और व्यवहार इतना सौम्य है कि आप न उनसे बहस कर सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं," तिवारी की

कार्यशैली से खिसियाये हुए एक इंका महासचिव का 'माया' से कहना था।

सांसदों की शिकायत: झक मार कर सांसदों से कहा गया "अब हम कुछ नहीं कर सकते आप खुद इस बाबत प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए।" एक-एक कर उत्तर प्रदेश के लगभग दो दर्जन से ज्यादा सांसद समय-असमय राजीव गांधी के पास जाकर अपना दुखड़ा रो आये। प्रधानमंत्री ने सभी को भरोसा दिया कि 'जल्द ही सब ठीक हो जायेगा।' "पर ठीक होता तो कैसे! प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक को तो पलक झपकते बदल सकते हैं, पर इलाके के डीएम, एसपी से लेकर दरोगा तक का तबादला तो मुख्यमंत्री के ही हाथ में है। इसमें दिल्ली क्या कर लेगी।" तिवारी से नाराज पूर्वांचल के एक इंका सांसद मजबूरी का खुलासा करते हैं।

इसी बीच शंका के एक दूसरे बीज ने भी जन्म लिया। प्रदेशों में तमाम बोर्ड और कारपोरेशनों के चेयरमैन और प्रमुखों की नियुक्तियों की बाबत अभी तक दिल्ली और मुख्यमंत्रियों के बीच एक अलिखित-अनकहा करार यह था कि मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करने से पहले सूची प्रधानमंत्री निवास भेज देते थे। प्रधानमंत्री सूची देख कर संबंधित राज्य को देख रहे अपने महासचिव या 'सलाहकार' को दे देते थे। प्राय: सूची में कोई फेरबदल नहीं होता था। पर यदि प्रधानमंत्री को किसी नाम को बदलना होता था, तो वे सूची पर पेंसिल से निशान लगा कर अपनी पसंद का नाम लिखवा देते थे जिसे महासचिव या उस राज्य को देख रहा सलाहकार मुख्यमंत्री से बात कर अंतिम शक्ल दे देता था। अन्य राज्यों में तो इस बाबत ज्यादा सतर्कता कभी नहीं बरती गयी, पर उत्तर प्रदेश में जरूर इस अलिखित नियम का पूरी निष्ठा से पालन किया जाता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रधानमंत्री तक सीधी सिफारिशें उत्तर प्रदेश से ही आती थीं। दौरों या प्रधानमंत्री निवास पर 'प्रात: दर्शन' में शामिल होने के लिए आये उत्तर प्रदेश के नेताओं, प्रतिनिधिमंडलों को प्रधानमंत्री आश्वासन दे देते थे। इसकी प्रक्रिया यह थी कि उस समय प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकारे गये प्रार्थनापत्र को 'मार्क' करके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देख रहे इंका महासचिव को दे दिया जाता था। जब मुख्यमंत्री बोर्ड या कारपोरेशन के चेयरमैनों की सूची दिल्ली भेजते थे, तो प्रधानमंत्री द्वारा पहले से 'कमिट' किये गये मामलों की फाइल को साथ रख कर सूची को अंतिम शक्ल दे दी जाती थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान, जहां करोड़ों-अरबों के सालाना बजटवाले इन बोर्डों-कारपोरेशनों के चेयरमैनों की कीमत बढ़ी, वहीं इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि दिल्ली संतुष्ट रहे।

पर तिवारी ने पूरी सहजता के साथ इस प्रक्रिया को ताक पर रख दिया। जब भी दिल्ली में बोर्ड और कारपोरेशनों के चेयरमैनों की बात हो, वे हर बार 'अभी देखते हैं, करते हैं' की मुद्रा के साथ बात टाल गये। वहीं दिल्ली से उनके लौटने के बाद आलाकमान को खबर मिली कि तिवारी ने लखनऊ में कभी पांच तो कभी सात बोर्डों के चेयरमैनों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली में तिवारी के विरोधियों के पास इसका पूरा अंकगणित है जिसके अनुसार उन्होंने अब तक कुल ४५ बोर्डों-कारपोरेशनों के चेयरमैन नियुक्त किये, जिनमें बीस को राज्यमंत्री और शेष को उपमंत्री का दर्जा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से दो चार को छोड़ कर शायद ही कोई राजीव गांधी से या दिल्ली दरबार में उत्तर प्रदेश के लेखा-जोखा रखनेवाले महासचिव गुलाम नबी आजाद से मिला हो। दिल्ली में इन नियुक्तियों को व्याख्यायित किया गया कि राज्य या उपमंत्री का दर्जा पाये ये चालीस महानुभाव सिर्फ तिवारी के प्रति वफादार हैं और जिनका दिल्ली या एआईसीसी से कोई लेना-देना नहीं है। बहरहाल, इस माहौल में यह बात फैलायी गयी कि तिवारी ने गुपचुप चालीस-पैंतालीस ऐसे लोगों का 'अतिरिक्त मंत्रिमंडल' खड़ा कर लिया है जो सिर्फ उन्हीं के कट्टर वफादार हैं। तिवारी इसका खंडन अपने ढंग से करते हैं, "इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझे निर्णय करने की स्वतंत्रता दे रखी है। मैंने उन्हीं लोगों को नियुक्त किया है जो जाने-माने जनसेवक हैं।" (देखिए साक्षात्कार)

दिल्ली की इच्छा के विरुद्ध: इस बीच एक और घटना घट गयी। उत्तर प्रदेश के नगर महापालिकाओं के चुनावों के नतीजों को देखने के बाद दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि फिलहाल लखनऊ और इलाहाबाद के चुनाव न कराये जायें। बाकी जगह हुए चुनावों के बाद इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी आलाकमान के लिए तैयार किये गये 'गोपनीय नोट' का लुब्बेलुबाब यह था कि लखनऊ और इलाहाबाद में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं है। यहां यदि चुनाव हुए, तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल होगा। क्योंकि ये दोनों ही शहर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यहां यदि कांग्रेस हारी, तो इसका आगामी चुनाव पर भी असर पड़ेगा और विपक्ष के समर्थन में अतिरिक्त हवा बनेगी। बताया जाता है कि तिवारी को भी इस बाबत दिल्ली की राय बता दी गयी थी। लखनऊ के मसले पर सांसद शीला कौल भी यही राय जाहिर कर चुकी थीं।

पर अचानक एक दिन दिल्ली को सूचना मिली कि तिवारी ने लखनऊ में इलाहाबाद और लखनऊ की नगर महापालिकाओं के चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इंका महासचिवों ने प्रधानमंत्री से पूछा, "क्या आप से तिवारीजी की इस बाबत बात हुई है?" राजीव गांधी ने साफ इनकार करते हुए उलटे महासचिवों से कहा, "नहीं, मुझे लगा आप लोगों ने आपस में बात करके इसे अपने स्तर पर ही तय कर लिया हो।" प्रधानमंत्री और महासचिव दोनों ही हतप्रभ। दिल्ली दरबार के सिपहसालार ने फिर कमर कसी। तिवारी के दिल्ली आने पर पूछा गया कि आपने कैसे चुनाव घोषित कर दिये? शांत तिवारी ने पूरे बखेड़े को तिनके-सा उड़ाते हुए संक्षिप्त-सा सौम्य जवाब दिया, "मैंने सोचा जब

'उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा'— बयान जारी करनेवाले आजाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जहां उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी हैं, तो वहीं तिवारी के प्रबल विरोधियों में माने जाते हैं।

गुलाम नबी आजाद

सभी जगह स्थानीय निकायों के चुनाव हो ही गये हैं, तो इन दो जगहों में भी हो जाने दिये जायें।" यों इस आरोप से बचने के लिए ये चुनाव जरूरी थे कि राजीव गांधी निचले स्तर तक प्रजातंत्र को मजबूत करने की बात तो करते हैं, लेकिन इलाहाबाद और लखनऊ के चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन इन दोनों जगहों में चुनाव में हुई इंका की फजीहत से दिल्ली की खीज और शक में बदली। इलाहाबाद में तो इंका हार ही गयी, लखनऊ में भी इंकाई उम्मीदवार को बड़ी मुश्किल से तिवारी जिता पाये।

एक के बाद एक घट रही इन घटनाओं के बीच हल्के-हल्के सुलगती शंका की आग को जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह के बयान ने हवा दी, तो वहीं अखबारों-पत्रिकाओं में छपी खबरों की 'एनेलिसिस' करने के लिए तैनात गुप्तचर सेवा के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 'नोट' भी कम चौकाने वाला नहीं था। पिछले एक वर्ष में देश भर के अखबारों में खास कर हिन्दी अखबारों-पत्र-पत्रिकाओं में तिवारी के संबंध में छपी खबरों के गहरे विश्लेषण के जो नतीजे थे, उनमें दो बिन्दु खासे महत्वपूर्ण माने गये। एक, वे अखबार जो सामान्य रूप से कांग्रेस विरोधी माने जाते रहे हैं और जिन्होंने राजीव गांधी से लेकर नीचे तक के कांग्रेसियों के खिलाफ धुआंधार लिखा है, उनमें भी साठ फीसदी खबरें परोक्ष रूप से तिवारी के पक्ष में या उनके विरोधियों पर हमले करने वाली थीं। सिर्फ दस फीसदी खबरें ऐसी थीं, जिन्हें हल्के-फुल्के तौर पर तिवारी के खिलाफ कहा जा सकता है।

केसी पंत

स्थिति यह थी कि उप्र के दिल्ली में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों में पेट्रोलियम राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त और कुछ हद तक मोहसिना किदवई को छोड़कर एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो तिवारी के बचाव में बोलने खड़ा हुआ हो।

तिवारी पर हमले: वहीं, इस माहौल में प्रधानमंत्री के चारों ओर बैठे हर एक शक्तिशाली सलाहकार से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद उप्र के वरिष्ठ मंत्री तक एक के बाद एक तिवारी के खिलाफ अपनी अपनी शिकायतों—नाराजगियों का बारूद दागने लगे। चाहे वे गुलाम नबी आजाद हों या केसी पंत या दिनेश सिंह। यद्यपि सभी की नाराजगी के अपने अलग-अलग कारण थे। कुल मिला कर स्थिति यह थी कि उप्र के दिल्ली में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों में पेट्रोलियम राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त और कुछ हद तक मोहसिना किदवई को छोड़कर एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो तिवारी के बचाव में बोलने खड़ा हुआ हो।

गुलाम नबी आजाद से तिवारी की पटरी न बैठने का कारण जहां उप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव थे, तो बलराम सिंह यादव की तिवारी से खिन्नता का कारण जनता दल नेता मुलायम सिंह यादव के प्रति तिवारी का 'प्रेमपूर्ण' व्यवहार था। एक ही शहर इटावा से लगभग एक ही तरह की राजनीति शुरू करनेवाले बलराम सिंह और मुलायम सिंह जहां एक ही बिरादरी के हैं, वहीं आज राजनीति से लेकर निजी स्तर पर दोनों दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं और दोनों की शत्रुता किसी से छिपी नहीं है।

उत्तर प्रदेश के इंचार्ज राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश इंका की दुर्दशा को लेकर जब-जब प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव को कसा, यादव हर बार सारी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी अपने सिर से उतार कर मुख्यमंत्री और प्रशासन के माथे मढ़ गये। दिल्ली के डंडे से हर बार अपनी खाल बचाने के लिए बलराम सिंह यादव को 'इटावा' के रूप में सबसे बड़ी ढाल मिल गयी। "मेरे अपने जिले इटावा में ही हालत यह है कि जिले का असली मुख्यमंत्री तो जैसे मुलायम सिंह यादव को बना दिया गया हो। मुलायम सिंह डीएम से लेकर दरोगा तक अपनी मर्जी से जिले में नियुक्त करवाते हैं और तिवारी करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल क्या रह जायेगा?"—बलराम सिंह यादव खेमे से यह बात दिल्ली में इंका महासचिवों, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर आलाकमान तक एक नहीं, बल्कि कई दफा पहुंचायी गयी।

बलराम सिंह यादव खेमे की इस बहुप्रचारित शिकायत का शायद ही कोई बड़ा असर पड़ा होता, यदि इस बीच दिल्ली दरबार में सबसे निर्विवाद माने जाने वाली शीला दीक्षित की भी तिवारी से टकराने की नौबत न आ गयी होती। मृदुता और सौम्यता की इन दो 'प्रतिमूर्तियों' के बीच हुई इस 'तनातनी' का कारण भी मुलायम सिंह यादव ही बन गये। अपने निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज के दौरे पर आयीं शीला दीक्षित का उनके कार्यकर्ताओं ने लगभग घेराव सा कर लिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने सीधा सवाल पूछा, "उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, कांग्रेस की या मुलायम सिंह यादव की?" कार्यकर्ताओं के इस अप्रत्याशित सवाल से शीला दीक्षित का चौंकना स्वाभाविक था। इससे पहले कि वे कार्यकर्ताओं को समझायें, उनके सामने कन्नौज-कानपुर इटावा इलाके (मुलायम सिंह का प्रभाव क्षेत्र) में मुलायम सिंह यादव और उनके रिश्तेदारों—सिपहसालारों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों व अन्य संस्थाओं को खुद मुख्यमंत्री द्वारा अपने राहत कोष व दूसरे मदों से दिये गये करीब चालीस लाख रुपए के सरकारी अनुदानों की ब्यौरेवार सूची पेश कर दी गयी। वहीं इलाके में सरकार द्वारा दिये गये बंदूकों-रायफलों के लाइसेंसों की सूची भी दिखायी गयी। कार्यकर्ताओं ने इस सूची में से शीला दीक्षित को मुलायम सिंह यादव समर्थकों के नाम गिनाने शुरू किये। "हमें अपने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को बंदूक का एक लाइसेंस दिलाने में दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। उस पर भी, कोई भरोसा नहीं कि लाइसेंस मिले। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव विपक्ष में रह कर भी अपने लोगों को धड़ाधड़ लाइसेंस दिलवा देते हैं। इस पर आप कहती हैं कि संगठन खड़ा करो," एक स्थानीय इंका नेता ने अपना दर्द जाहिर किया।

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार उस समय तो शीला दीक्षित ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत किया। पर उसके बाद ही नारायण दत्त तिवारी से हुई मुलाकात में उनका सारा गुबार बाहर था। "मैं नहीं समझ पाती हूं यह कौन-सी राजनीति है। आप वरिष्ठ हैं, हमारे सम्माननीय हैं। आपको मालूम है कि इस इलाके में मुलायम सिंह के लोग ऊधम मचाये रहते हैं, ऐसे में आप सीधे मुख्यमंत्री कोष से उन्हें पैसे बांटेंगे, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल रह

जायेगा,'' शीला दीक्षित का कहना था। जानकार सूत्रों के अनुसार पहले तो तिवारी ने साफ किया कि यह धन उन्होंने नहीं वीर बहादुर सिंह ने आवंटित किया था। फिर यह बात निकल कर आयी कि अब वीर बहादुर तो रहे नहीं, इसलिए उनकी बात करना बेकार है। यदि मान लें कि वे आर्डर कर गये थे तो पैसा क्या अभी चुनाव के ऐन वक्त पर बंटना था। कुल मिलाकर दोनों के बीच हुई तकरार में एक मौका वह भी आया, जब कहते हैं कि तिवारी ने यहां तक कहा कि यदि लोग इस तरह मेरे बारे में सोचते हैं, तो मैं यह छोड़कर घर बैठ जाता हूं। यद्यपि 'माया' द्वारा इस 'बातचीत' की बाबत पूछे जाने पर शीला दीक्षित ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया।

परिवर्तन की अफवाह: इसी बीच दिल्ली और लखनऊ में एक अफवाह उडी कि तिवारी की जगह शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कर लखनऊ भेजा जा रहा है। तिवारी विरोधियों को जैसे ही शीला दीक्षित और तिवारी के बीच हुई इस 'बातचीत' की भनक मिली, वे इसे जोरों से ले उड़े। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाकर भेजने की अफवाह और तेज हुई। मकसद साफ था कि तिवारी और शीला दीक्षित के संबंधों में आयी खराश को खाई की शक्ल देकर दिल्ली दरबार में शीला दीक्षित जैसी शक्तिशाली सलाहकार को भी तिवारी विरोधी खेमे की झोली में डाल दिया जाये। शंका और संदेह के इस माहौल में यह कोशिश थोड़ा बहुत रंग लायी भी।

'माया' द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर शीला दीक्षित का साफ जवाब था, ''मेरे मुख्यमंत्री बनाने की अफवाह सरासर झूठी थी। मेरे इस वक्त मुख्यमंत्री बन कर जाने का सवाल ही नहीं उठता, न मेरा इतना बड़ा कद है कि मैं चुनाव के वक्त इतने बड़े प्रदेश का भार उठा पाऊं। इसके लिए तिवारीजी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनसे ज्यादा सही व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता।'' शीला दीक्षित इस बात से साफ इनकार करती हैं कि तिवारी को हटाने का कोई 'मूव' था। पर वहीं वे मानती हैं, ''तिवारीजी की अपनी एक कार्यशैली है। हो सकता है कि किसी को उस कार्यशैली से कभी थोड़ा बहुत मतभेद या परेशानी हो। हरेक की अपनी-अपनी कार्यशैली होती है। पर जहां तक उनकी राजनीतिक दृष्टि, सूझबूझ और निष्ठा का सवाल है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।''

नाजुक विवाद: तिवारी को हटाये जाने की किसी मुहिम से इनकार तो गुलाम नबी आजाद भी करते हैं। पर कार्यशैली का सवाल हर जगह फंसता है। गुलाम नबी आजाद के साथ यह सवाल तब फंसा, जब उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के चुनाव के बाद आलाकमान ने चुनाव परिणामों की समीक्षा रपट तैयार की। इस चुनाव में हर जगह दूसरे प्रदेशों के तीन-तीन सांसदों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। पांच जगहों से पर्यवेक्षकों ने लौट कर रपट दी कि उन इलाकों में कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए हारा, क्योंकि वहां के कांग्रेसी मंत्री खुद इंकाई प्रत्याशी के खिलाफ थे या विपक्षी प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त के इलाके में तो दिल्ली से भेजे गये एक पर्यवेक्षक सांसद को अपने कपडे-लत्ते से हाथ धोकर रात दो बजे दिल्ली भाग कर आना पड़ा। उसके अनुसार ब्रह्मदत्त के लोगों ने उसका पायजामा तक उतरवा लिया था।

> "उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, कांग्रेस की या मुलायम सिंह यादव की?" कार्यकर्ताओं के इस अप्रत्याशित सवाल से शीला दीक्षित का चौंकना स्वाभाविक था।

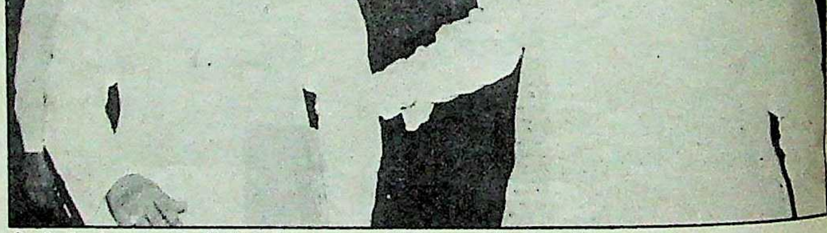

विपक्षियों को अपना बनाने में माहिर: मुलायम सिंह यादव और तिवारी

राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस समीक्षा-रपट पर खासी गंभीरता से चर्चा हुई। आखिरकार राजीव गांधी ने फैसला दिया, ''उत्तर प्रदेश को देख रहे पार्टी महासचिव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करती है और यदि श्री आजाद उचित समझें, तो अनुशासनहीनता की गंभीरता को देखते हुए इन पांचों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाये।'' राजीव गांधी का यह फैसला आज भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उस बैठक की 'कार्यवाही' में दर्ज है। बताते हैं कि अधिकार मिलते ही आजाद ने फैसला सुना दिया कि इन पांचों मंत्रियों को हटा दिया जाये। हटाये जाने वाले मंत्रियों में जहां नारायण दत्त तिवारी के सबसे नजदीकी केंद्रीय राज्यमंत्री ब्रह्मदत्त थे, तो वहीं चार उप्र के मंत्री थे। इनमें अरुण कुमार सिंह मुन्ना और कौकब हमीद भी शामिल थे। संयोग से ये दोनों ही गुलाम नबी आजाद के निकटवर्ती माने जाते हैं।

दिल्ली में तय किया गया कि पहले तिवारी को इन चारों राज्य मंत्रियों की सूची दे दी जाये। जब ये चार मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बाहर हो जायें, तो दिल्ली में ब्रह्मदत्त को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाये। लखनऊ में हुए सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तिवारी को चुपचाप इन चार मंत्रियों की सूची थमा दी। पर तिवारी ने चारों मंत्रियों को बुलाकर इसकी जानकारी दे दी। चारों मंत्री और उनके समर्थकों ने दिल्ली दौड़ना शुरू कर दिया। गुलाम नबी आजाद को कोसने और अपनी पैरवी के लिए जोरदार लाबिंग के शुरू हुए इस खेल में पार्टी को अनुशासित करने के लिए उठाये जा रहे इस कदम ने और अनुशासनहीनता फैलानी शुरू कर दी। चारों मंत्रियों को हटाने की बात खुद ठप पड़ गयी और जब राज्य के चार मंत्री नहीं हटे, तो दिल्ली में भला उसी अपराध के लिए ब्रह्मदत्त को कैसे हटाया जाता?

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति से चकरघिन्नी खाये गुलाम नबी आजाद छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीने में यकीन करने लगे हैं। इस घटना के बारे में पूछने पर किसी भी टिप्पणी से इनकार करने वाले आजाद ''तिवारीजी को हटाये जाने का कोई सवाल ही

नहीं उठता, वे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे" की औपचारिक टिप्पणी से आगे उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी राजनीति के संबंध में भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं।

गुलाम नबी आजाद और शीला दीक्षित की इन परेशानियों के अलावा तिवारी से दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी रक्षा मंत्री केसी पन्त को है। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र से आये इन दोनों (तिवारी और पंत) कांग्रेसी नेताओं की 'आदि शत्रुता' तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद तब और भी तेज हो गयी, जब तिवारी ने मुख्यमंत्री के रूप में जहां एक तरफ कुमाऊं के एक के बाद एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेताओं को अपनी शरण में लेना और उपकृत करना शुरू किया, वहीं उन्होंने अल्मोड़ा के इंकाई सांसद हरीश रावत से राजनीतिक मैत्री कर पूरे क्षेत्र के जातीय राजनीतिक समीकरण को ही बदलना शुरू कर दिया। इसका अगला क्रम काशीपुर में खासा असर रखनेवाले अकबर अहमद डंपी का तिवारी की मार्फत कांग्रेस में पुनः गृह प्रवेश था। पंत खेमा उस दिन चौंका जब अकबर अहमद डंपी जैसे गर्ममिजाज नेता ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात के बिना ही कांग्रेस में आना कबूल कर लिया। साथ ही यह बयान भी दिया, "मेरी तिवारीजी से बात हो चुकी है, और यह काफी है। राजीवजी यदि बात करना चाहेंगे, बुलायेंगे तो मिल लूंगा।"

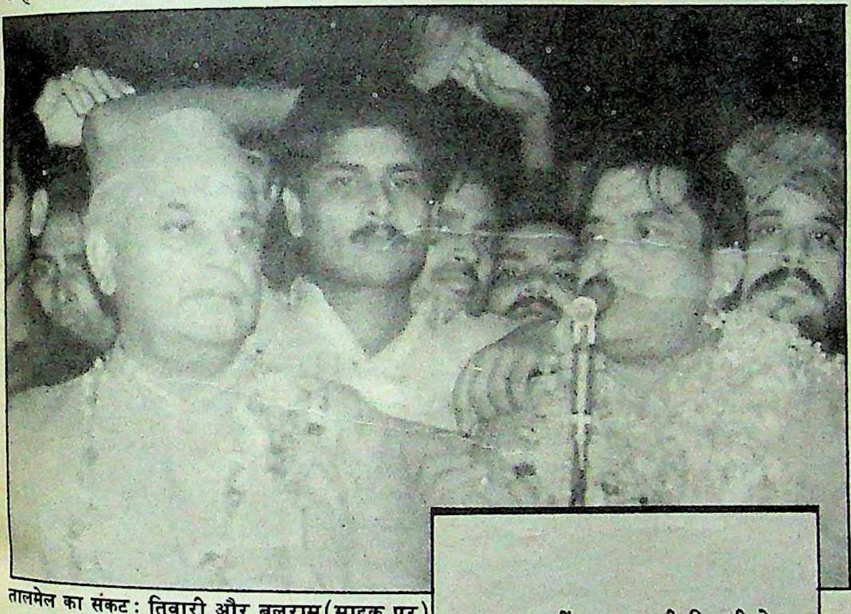

तालमेल का संकट: तिवारी और बलराम (माइक पर)

बलराम सिंह यादव की तिवारी से खिन्नता का कारण जनता दल नेता मुलायम सिंह यादव के प्रति तिवारी का 'प्रेमपूर्ण' व्यवहार था।

हरीश रावत, डंपी और तिवारी के इस त्रिगुट के बाद केसी पंत के लिए अपने रक्षा मंत्रालय के फौज-फाटे, हेलीकाप्टरों के काफिले और दौरों के बावजूद कुमाऊं में पैर जमा पाना लगभग नामुमकिन-सा हो गया। ऐसी हालत में पंत के पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि वे नयी दिल्ली की 'परदेसी' सीट पर अपना राजनीतिक जुआ खेलते रहें। इससे बचने के लिए पंत ने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र तिवारी के खिलाफ दागा। यानी प्रधानमंत्री निवास में अपनी निकटता के आधार पर राजीव गांधी के दिमाग में तिवारी के खिलाफ शंकाओं को जम कर हवा दी जाये और किसी तरह चुनाव से पहले तिवारी को हटा कर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना कर कुमाऊं से अपनी सीट तैयार की जाये।

पंत की इस मुहिम को कैबिनेट में केंद्रीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह से भी खासी मदद मिली। आठ सितंबर तक दिल्ली में एक नौबत यह आ गयी कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए दबे स्वरों में अलग-अलग अटकलें लगाने लगे।

कोई विकल्प नहीं: पर समस्या नारायण दत्त तिवारी को हटाना नहीं, बल्कि उनकी जगह किसी को बिठाने की थी जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगा सके। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में सदा से चले आ रहे चिरपरिचित नाम—लोकपति त्रिपाठी, नरेन्द्र सिंह और बलराम सिंह यादव चर्चा में आये और अफवाह बन कर रह गये। दिल्ली में एक वरिष्ठ इंकाई नेता का कहना था, "असली समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में तिवारीजी के बाद दूर तक कोई नेता ऐसा है ही नहीं, जिसे उनका विकल्प बनाया जा सके।"

और निश्चय ही ऐन चुनाव के वक्त किसी और को मुख्यमंत्री बना कर उसे स्थापित करने का कांग्रेस के पास न समय है, न ही कोई खतरा उठाने की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ तिवारी और उनकी 'कार्यशैली' से पैदा हुए संदेह अपने दस्तावेजों के साथ साफ-साफ शक की भाषा बोल रहे थे। इस हालत में फंसे दिल्ली दरबार और नारायण दत्त तिवारी को दो विपरीत ध्रुवों से महत्वपूर्ण मदद मिली। एक तरफ जहां अब तक दर्शक बने खड़े केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने पूरे माहौल को शांत कर समझौता कराने में पहल की, तो वहीं अपनी आदत के विपरीत मौन साधे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कल्पनाथ राय ने धवन और तिवारी के बीच पुल का काम करना शुरू किया।

११ सितंबर की रात प्रधानमंत्री से तिवारी की मुलाकात के पहले बूटा सिंह और तिवारी के बीच गुपचुप दो लंबी वार्ताएं हो चुकी थीं जिनका ब्यौरा लेकर सिंह प्रधानमंत्री से मिल चुके थे। बताते हैं कि तिवारी की बूटा सिंह से वार्ता का लुब्बेलुबाब यह था, "राजीव गांधी मेरे नेता हैं, रहे हैं, और रहेंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री के निकट रहने वाला हर व्यक्ति मेरा नेता हो जाये।" तिवारी का संकेत साफ था जिसे समझने में बूटा सिंह जैसे व्यक्ति को देरी भी नहीं लगी। प्रधानमंत्री से बूटा सिंह की इस बाबत हुई बातों का कुल एक नतीजा था कि फिलहाल कोई छेड़छाड़ न की जाये। यदि एक तरफ से शिकायतों को कुरेदने-पूछने का सिलसिला चलेगा, तो हालत बदतर ही होगी।

जिसके बाद ही शंका-आशंका के घुमड़ते बादलों के बीच ग्यारह सितंबर की रात धवन प्रधानमंत्री निवास में तिवारी को फौरन याद करते नजर आ रहे थे। देर रात तिवारी की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बातचीत हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए थे—कुछ अदद प्रशंसा सूचक शब्द, सम्मान देती भंगिमाएं, बातचीत शुरू करने के बहाने के लिए उत्तर प्रदेश की दो चार विकास योजनाओं की चर्चा और यमुना-कोसी परियोजना जैसे शुद्ध औपचारिक मुद्दे। साथ ही, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के तीन दिन बाद दौरे को अंतिम शक्ल दी गयी और अतिरिक्त नम्रता के साथ कुछ ही देर में दोनों के पास एक दूसरे को कहने पूछने का कोई मुद्दा नहीं बचा। तिवारी लौट आये। न प्रधानमंत्री ने ही शंकाओं की बाबत पूछा, न नारायण दत्त तिवारी ने कोई जवाब दिये। यक्ष प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था और है। और बिना कोई समझौता हुए दोनों के बीच अपने किस्म का अद्भुत समझौता हो चुका था। जिसके नतीजे थे अगले ही दिन १२ सितंबर को गुलाम नबी आजाद का तिवारी के पक्ष में बयान और दो दिन बाद ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी का उत्तर प्रदेश दौरे में तिवारी की प्रशंसा में दिया गया बयान।

—पुनीत टंडन

साक्षात्कार: नारायणदत्त तिवारी

'राजीव का विश्वास मुझ पर है'

माया: उत्तर प्रदेश के सांसदों को यह शिकायत है कि आप उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते, जिनको वे चाहते हैं।

नारायण दत्त तिवारी: मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हमारे किन्हीं सांसद मित्र ने ऐसी कोई शिकायत की है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे सांसद मित्रों की मेरे पर बड़ी कृपा रही है और आज भी है। मैं तो यही कहूंगा कि आमतौर पर हमारे सांसद स्थानांतरणों के बारे में बहुत कम कहा करते हैं। ज्यादातर वे अधिकारियों के काम करने के ढंग, उनकी कार्यक्षमता, कार्यक्रमों को लागू करने की शक्ति, दौड़-धूप करने की क्षमता आदि की समालोचना-प्रशंसा करते रहे हैं। कभी-कभी स्थानांतरणों का सुझाव देते हैं। उनके सुझाव उचित हुए, तो अवश्य माने गये और कभी सहमति नहीं बन पायी, तो उनको समझा दिया गया कि कठिनाई क्या है और वे मान गये। बहरहाल, मुझे कोई सीधी जानकारी नहीं है कि सांसदों को कोई शिकायत है।

माया: उत्तर प्रदेश के सांसदों की पिछली बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्याय व्यवस्था, बिजली संकट आदि को लेकर क्या आपकी आलोचना हुई थी?

तिवारी: शिकायतों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह प्रश्न है। बहुत सी शिकायतें सही हो सकती हैं, लेकिन वे सरकार का बुरा चाहने के लिए नहीं की जातीं। इतने बड़े प्रदेश में कहां-क्या हो रहा है, इसकी सूचना देने के लिए होती हैं। सांसदों-विधायकों का कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करें और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच रही हैं या विकास कार्यों के कार्यान्वयन में कहीं कोई कमी है, तो उन्हें बताना चाहिए, ताकि यथाशीघ्र ठीक किया जा सके। मैं ऐसी शिकायतों का बुरा नहीं मानता। मैं अपना फर्ज मानता हूं कि जो उचित शिकायतें हैं उनको सुनूं और उनको दूर करूं।

माया: क्या यह बात सही है कि पांच दिन के इंतजार के बाद आपको राजीव गांधी से मिलने के लिए दिल्ली में पांच मिनट का समय मिला?

तिवारी: यह अफवाह है। मेरे छोटे भाई सम्माननीय लोकपति त्रिपाठीजी की धर्मपत्नी माननीया सांसद चंद्रा त्रिपाठी का निधन हो गया था, इसलिए मुझे बनारस जाना पड़ा। एक दिन तो उसी में लग गया। रात को देर से लौटा। दूसरे दिन हमारी बैठकें लगी हुई थीं। गंगा एक्शन प्लान की बैठक हुई, वहां प्रधानमंत्री से बातें हुईं। फिर अपनी पार्टी की बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्रीजी से जितनी बातें आवश्यक थीं, वे हुईं। उसी के दो दिन बाद पांच घंटे मीटिंग हुई प्रधानमंत्रीजी से। तो अफवाह का तो स्वयं निराकरण हो गया। पहले भेंट का समय मांगा ही नहीं था, हमने, क्योंकि बातें हो चुकी थीं। तो यह कहना सही नहीं है कि प्रधानमंत्रीजी से भेंट नहीं हुई। फिर यह कोई उचित नहीं है कि जितनी बार हम दिल्ली जायें, प्रधानमंत्रीजी का समय लें।

माया: वीपी सिंह बार-बार आपकी तारीफ करते हैं। इससे कई तरह की अटकलबाजियां जन्मी हैं। आप इस स्थिति का कैसे आकलन करते हैं?

तिवारी: सामान्यतया कोई व्यक्ति किसी की तारीफ करे, तो बुरी बात नहीं। मैं इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखता। लेकिन हम सब राजनीति में हैं और चुनाव का समय है। इसीलिए अगर यों कहा जाये कि जनता दल की एक यह भी रणनीति रही है कि आपस में हमारा तालमेल न रहे, संबंध मधुर नहीं रहें। इसलिए इस तारीफ में कोई रणनीति है। जैसे कुछ लोगों ने उड़ा दिया कि जगन्नाथ मिश्र, अर्जुन सिंह, पवार साहब और मैं मिलकर कुछ कर रहे हैं, जबकि न ऐसी कोई बात हुई, न कोई भेंट हुई, लेकिन समाचार हो गया। कुछ हमारे मित्रों ने यह भी कह दिया कि वे (तिवारीजी) हटा दिये जायेंगे। किसी ने कहा कि अपमान हो रहा है। तमाम बातें कही गयीं। जो भी कहा गया, किन्हीं के भी द्वारा कहा गया हो, उसका कोई आधार नहीं।

माया: कुछ लोग कहते हैं कि आपकी निष्ठा आपकी योग्यता के कारण संदिग्ध है। मतलब यह है कि आप कांग्रेस में वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव की दृष्टि से योग्यतम हैं। आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा है। इसीलिए आपको एक आदर्श विकल्प माना जाता है। आपकी राय क्या है?

तिवारी: मैं तो यह समझता हूं, मुझमें बहुत अयोग्यताएं हैं, इसलिए यदि कोई कहे कि मैं बहुत योग्य हूं, तो मैं समझता हूं यह मेरे ऊपर उसकी अनुकंपा ही है। यह कहना कि मेरी योग्यता के कारण मुझे कठिनाई हो रही है, निराधार बात है। मैं अपने को योग्य तो नहीं समझता, लेकिन यह चेष्टा अवश्य करता हूं कि अयोग्य साबित न होऊं।

माया: क्या कांग्रेस में आपसे वरिष्ठ कोई राजनेता है जो हर संकट के समय कांग्रेस में ही बना रहा हो, यानी कांग्रेस के बाहर न गया हो?

तिवारी: कई होंगे। बहुत स साथी होंगे। बिहार में हमारे सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री हैं, वे मेरे से वरिष्ठ हैं।

माया: लेकिन वे तो कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस में आये हैं?

तिवारी: मैं तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहूंगा।

माया: हम तो देखना चाहेंगे।

तिवारी: यह तो उचित नहीं है कि मैं स्वयं ही कहूं कि मैं सीनियर हूं। पूरी जानकारी मेरे पास है भी नहीं हरेक के बारे में। इसलिए इस प्रश्न से थोड़ा मुझे अलग ही रखें, तो बड़ी कृपा होगी।

माया: आपने करीब पैंतालीस निगमों आदि के अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। क्या इनमें ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लिया, जिसकी सिफारिश आलाकमान ने की थी?

तिवारी: इससे तो यह कहा जा सकता है कि मुझ पर ऊपर से कोई दबाव नहीं है। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि मुझे मंत्रिमंडल-विस्तार की अनुमति नहीं दी जा रही और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मैं ऊपर के आदेश नहीं मानता। ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? आपने निगमों की जो संख्या बतायी है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। काफी निगम पहले से चले आ रहे हैं। अब जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, वे अनुभवी हैं और अनेक का जनसेवा का लंबा काल रहा है। मैं नहीं समझता इन नियुक्तियों को लेकर ऊपर-नीचे कोई शिकायत की कोई बात हो।

माया: १९८४ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीपी सिंह और मुख्यमंत्री के रूप में आप में अटूट सामंजस्य था, जिससे कांग्रेस को अभूतपूर्व

सफलता मिली थी, लेकिन आज आप में और वर्तमान अध्यक्ष बलराम सिंह के बीच ऐसा सामंजस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आपको चुनाव संचालन या प्रत्याशी चयन में कठिनाइयों का सामना नही करना पड़ेगा?

तिवारी: हर समय हरेक का स्टाइल अलग-अलग होता है। यह बात गलत है कि सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य की जितनी आवश्यकता है, उतना हो रहा है। अब भी बैठकें होती हैं, तो हम साथ रहते हैं। मैं प्रशासकीय काम में लगा हूं और वे (बलराम सिह) संगठन के काम में, इसलिए रोज बैठकें हों, यह संभव नहीं है।

माया: आगामी चुनाव में प्रत्याशियों का चयन काफी सोच-समझ कर होने पर ही चुनाव में सफलता हासिल करने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या आपके और आलाकमान के बीच प्रत्याशी चयन के बारे में बातें हो चुकी हैं? प्रत्याशियों के चयन में आप क्या आधार अपनाने जा रहे हैं?

तिवारी: कांग्रेस जैसे ऐतिहासिक दल में प्रत्याशियों के चयन की स्वतंत्रता किसी मुख्यमंत्री या अध्यक्ष को मिलने का प्रश्न नहीं उठता। यहां पर सामूहिक आधार पर काम होता रहा है। सबकी सलाह लेकर संसदीय बोर्ड, हाईकमान और फिर कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय को अंतिम रूप देते रहे हैं। यहां पर फ्री हैंड या किसी एक को अधिकार होगा, इसका प्रश्न उठता ही नहीं है। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मेरा अनुभव रहा है कि जब किसी प्रदेश के एक नेता के रूप में कार्य हुआ, तो अंततोगत्वा कुछ समय तक कार्य भले ही ठीक चला हो, लेकिन बाद में कठिनाइयां अवश्य आयी हैं। इसलिए जिसे हम आमतौर पर सामूहिक नेतृत्व कहते हैं, वही सफल रहा है। ऐसी हमारी मनोकामना ही नहीं है कि इस मामले में हमें स्वतंत्रता मिले। यह न उचित है, न संभव है, न ऐसा प्रदेश कांग्रेस या कांग्रेस के इतिहास में हुआ।

माया: अफवाहों में एक अफवाह यह भी है कि बंबई के एक शीर्ष पूंजीपति, जिनकी दिल्ली के सत्ता केंद्र में काफी पैठ है, आपकी खिलाफत कर रहे हैं?

तिवारी: मुझे नहीं मालूम। मुझे इसकी जानकारी नहीं।

माया: दिल्ली में देवीलाल की रैली को इस बात का एक सबूत और माना जा रहा है कि विपक्ष दिनोदिन एकजुट हो रहा है। इससे लगता है, कांग्रेस के एक प्रत्याशी का मुकाबला विपक्ष के एक प्रत्याशी से होगा। यदि ऐसा हुआ, तो आपको कांग्रेस की स्थिति कैसी नजर आ रही है?

तिवारी: यदि एक के मुकाबले में एक प्रत्याशी की टक्कर हुई, तो कुछ क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। लेकिन इसका फायदा भी हो सकता है कि जो धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शक्तियां हैं वे हमारी तरफ आ जायेंगी, पहले आयी भी हैं। यह अनिवार्य भी नहीं है कि सीधी टक्कर ही हो।

माया: क्या यह सही है कि मोहसिना किदवई, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और ब्रह्मदत्त आदि को छोड़कर उत्तर प्रदेश के अधिकांश केंद्रीय मंत्री आपसे नाराज हैं?

तिवारी: मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं। मैं तो यही जानता हूं कि सबका मुझ पर स्नेह रहा है और है।

माया: १९८० में कांग्रेस ने प्याज की महंगाई को मुद्दा बनाया था। इस समय चीनी का संकट है, इसलिए यह चुनावी मुद्दा होगा। इसके अतिरिक्त बाबरी मस्जिद—राम जन्मभूमि का मुद्दा है और बोफोर्स आदि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही। ये मुद्दे चुनाव में आपके लिए संकट पैदा करेंगे। इनसे आप कैसे निपटेंगे?

तिवारी: जहां तक महंगाई का प्रश्न है—विशेषकर चीनी का, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कीमतों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। बहुत से वे लोग जो चीनी के दाम बढ़ने की आलोचना कर रहे हैं, वे यह भी कह रहे हैं कि गन्ने के दाम पचास रुपए क्विंटल होने चाहिए। अब अगर यह कोई कहे कि इसका चीनी की कीमत से कोई तालमेल नहीं है, तो मैं कहूंगा हममें से कुछ लोग अधूरे अर्थशास्त्री हैं। यह कैसे हो सकता है कि गेहूं का दाम ज्यादा हो और राशन की दुकान में गेहूं सस्ता हो। कपास का दाम मुंहमांगा मिले और रूई सस्ती हो, कपड़ा सस्ता हो। यह विरोधाभास हम कैसे चला सकते हैं, यह अधूरा अर्थशास्त्र कैसे चलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगाई का मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन उसका उत्तर भी देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आमदनी बढ़ी है। उद्योग और खेती का उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक वृद्धि दर १२ प्रतिशत है। खेती-पैदावार में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पहला सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का कि प्रति व्यक्ति आमदनी की जो वार्षिक दर है, उसके अनुपात में यदि बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो कीमतें नहीं अखरतीं। इसका मतलब यह नहीं कि महंगाई या चोरबाजार का मुकाबला नहीं करना चाहिए। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि के मुद्दे का जहां तक सवाल है, सब कह रहे हैं कि हम मुद्दा नहीं बनायेंगे। मुझे तो अब भी आशा है और जहां तक मेरी सूचना है, अदालत का फैसला सभी पक्ष मानेंगे। अदालत ने आदेश दिया है कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। इसे सबको मानना चाहिए और कोई ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए कि शांति व्यवस्था भंग हो। उर्दू-हिंदी का तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। मैं भी हिंदी का एक विनम्र सेवक हूं। लेकिन यह सोचना गलत है कि हिंदी तभी शक्तिशाली बनेगी, जब दूसरी भाषाएं कमजोर होंगी। यदि उर्दू को चुनाव का मुद्दा बनाया जायेगा, तो विचारवान लोग साथ नहीं देंगे। किसी को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाने का प्रश्न है नहीं, हमने अपने विधेयक में साफ लिख दिया है कि बिहार में जो व्यवस्था की गयी है, वही हम भी रखेंगे। यह केवल उर्दू भाषा-भाषियों के लिए है। बिहार में जब किसी ने विरोध नहीं किया, तो आज विरोध क्यों हो रहा है। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी।

प्रधानमंत्री के बयान से वातावरण में जो संदेह की रेखा आने लगी थी, वह मिट गयी। मैं तो आभारी हूं कि उन्होंने अपने विश्वास को दोहराया। मैं तो हमेशा जानता हूं कि उनका विश्वास मेरे पर है, जैसे मित्रों और जनता-जनार्दन का भी यत्किंचित विश्वास सेवक पर है।

माया: आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करनी पड़ी कि आपको हटाने की कोई योजना नहीं है?

तिवारी: दो-चार अखबारों में यह बात आ रही थी कि तिवारीजी हटा दिये जायेंगे, तो उन्होंने एक भाषण के सिलसिले में स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया, नहीं तो काम करने में बाधा पड़ रही थी। यहां हमारे एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने हैडलाइन ही दे दी, उसको देखकर तो लोगों के और भी कान खड़े हो गये थे। प्रधानमंत्रीजी के बयान से वातावरण में जो संदेह की रेखा आने लगी थी, वह मिट गयी। मैं तो आभारी हूं कि उन्होंने अपने विश्वास को दोहराया। मैं तो हमेशा जानता हूं कि उनका विश्वास मेरे पर है, जैसे मित्रों और जनता जनार्दन का भी यत्किंचित विश्वास सेवक पर है।

माया: क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग आप और प्रधानमंत्री के बीच में अविश्वास की रेखा खींचने और उसे घनी करने में लगे हुए हैं?

तिवारी: मैं नहीं कह सकता। मैं अपने काम में लगा रहता हूं। मैं अफवाहों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर अफवाहों पर यकीन करना शुरू कर दिया, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। फिर अफवाहों को मैं अफवाह मानता हूं, सचाई नहीं। मैं अफवाहों का जिक्र भी नहीं करता। नहीं तो लोगों को लगेगा कि कहीं कोई सचाई है। हो सकता है मेरी ही किसी गलती के कारण मेरा कोई साथी अप्रसन्न हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं।

—अजय कुमार

मुख्यमंत्रियों की ट्रांसपोर्ट कंपनियां

सत्ता के पहियों पर दौड़ता धंधा

मध्यप्रदेश में गत एक दशक में यात्री-किरायों में ११८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियां तो मालामाल होती रहीं और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम एक अरब १७ करोड़ रुपए से भी अधिक के घाटे में उतर गया? आरोप सीधे मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर लग रहा है कि उन्होंने शासन के बजाय निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का हित साधन किया, क्योंकि खुद उनके परिवार की निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। क्या वास्तव में वोरा ने अपने परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुंचाया? प्रदेश के पूर्वमुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल के परिवार की भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, क्या उन्होंने भी ऐसा ही किया था। प्रस्तुत है, 'माया' की तहकीकात:

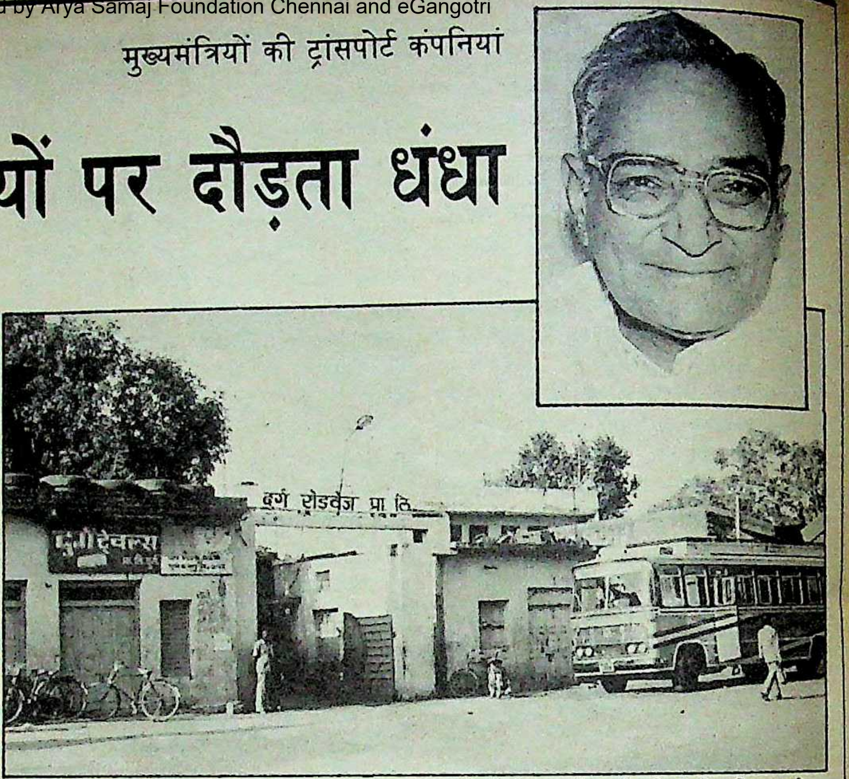

सरकारी बसें खस्ता हाल, निजी मालिक मालामाल: मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा (इनसेट) के परिवार की 'दुर्ग रोडवेज' का कार्यालय

अगर आपके पास निजी वाहन नहीं है और आप छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में पैठना चाहते हैं, तो आप रेलों और सरकारी बसों के भरोसे गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए किसी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की माल-असबाब से अंटी और मुसाफिरों से लदीफंदी बस में सफर करने के अलावा आपके समक्ष और कोई चारा नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जिस बस में बैठें, वह मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा अथवा भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल से संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनियों में से किसी कंपनी की बस हो।

पैंतीस-चालीस साल पहले छत्तीसगढ़ में कंबाइंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज कंपनी, रायपुर ट्रांसपोर्ट और मध्यप्रदेश ट्रांसपोर्ट की बसें चला करती थीं। छग (छत्तीसगढ़) में रास्ते तब भी कहीं कच्चे, कहीं पक्के, ऊबड़-खाबड़ और धूलभरे थे। बारिश में इन पर गाड़ियां चलाना यकीनन झंझट और जोखिम का काम था। कमोबेश यही स्थिति आज भी है, लेकिन इन तीन-चार दशकों में कई बातें हुई हैं। सबसे बड़ी बात—प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ी है, साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मिल्कीयत भी। जिस 'द रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रालि' ने १९४५ में पेट्रोलचालित आड़ी सीटोंवाली दो बसों से शुरुआत की थी, उसकी आज ४२ बसें छग की सड़कों पर चल रही हैं। मध्यप्रदेश ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रालि यानी एमपी ट्रांसपोर्ट की बसें आज भी रायपुर, कोरबा, बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच दौड़ती देखी जा सकती हैं।

इनमें कंबाइंड ट्रांसपोर्ट कंपनी विखंडित हो चुकी है और हाईवेज कंपनी १९५८ में 'डिजॉल्व' (भंग) कर दी गयी थी। इधर, यह कंपनी भंग हुई, उधर इसकी राख से तुरतफुरत तीन नयी कंपनियां उठ खड़ी हुईं। हाईवेज कंपनी को लोग भले ही भूल गये हों, किंतु इसकी कोख से जन्मी तीनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों—दुर्ग रोडवेज प्रालि, दुर्ग ट्रांसपोर्ट प्रालि और राजनांदगांव रोडवेज प्रालि इन दिनों सुर्खियों में हैं। इनमें से दुर्ग रोडवेज प्रालि—के खाते में बीहड़ रास्तों पर सफलतापूर्वक बसें आपरेट करने और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने के साथ-साथ यह श्रेय भी दर्ज है कि मप्र के वर्तमान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा बरसों इसके संचालक और कुछ काल के लिए इसके प्रबंध-संचालक रहे।

बीड़ी लॉबी की तर्ज पर अगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़े लोगों, मालिकों और हितचिंतकों को 'ट्रांसपोर्ट-लॉबी' की संज्ञा दें, तो कहा जा सकता है कि वोरा कभी इस लॉबी के सदस्य थे। इस दशक के शुरू में अर्जुन सिंह की सरकार में वे मंत्री बने, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट-बिरादरी से नाता तोड़ लिया। इस बीच बसों के चक्के और काल का पहिया घूमता रहा। वोरा प्रदेश इंकाध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय सरकार में मंत्री। जनवरी, १९८९ में वे बतौर मुख्यमंत्री भोपाल में लौटे। अचानक गड़े मुरदे उखड़े और धमाका हुआ कि वोरा शासकीय हितों के बजाय ट्रांसपोर्ट कंपनियों के हितों को प्रश्रय देते रहे हैं। यदि वे ट्रांसपोर्ट कंपनियों के हितों को न पोसते, तो बीते चार सालों के अंतराल में सरकारी खजाने में करीब ६३ करोड़ रुपए की रकम आती।

६३ करोड़ रुपए की राशि किसी भी दृष्टि से कम नहीं होती। पर वोरा पर अकेला यही आरोप चस्पा नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट कंपनियों और बिरादरी से उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कई बातें कही गयीं। प्रश्न उठा कि क्या 'मिस्टर क्लीन' और 'श्रीमान निष्कलंक' के तमगों से विभूषित मोतीलाल वोरा के हाथ भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने हैं? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के साथ-साथ यह पता करना भी जरूरी था कि वोरा ने निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के व्यावसायिक हितों को किस हद तक 'कैनोपी' (छत्रछाया) मुहैया की?

संबंध: किसी भी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी से वोरा का संबंध करीब २६ साल पुराना है। ४ मई, १९६३ को जब दुर्ग रोडवेज ने नये शेयर फ्लोट (जारी) किये थे, तब मोतीलाल वोरा ने पहली बार पांच-पांच सौ रुपए के दस शेयर खरीदे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ शेयर और खरीदे। अगले ही माह यानी २८ जून, १९६३ को वे दुर्ग रोडवेज प्रालि नामधारी कंपनी के डायरेक्टर हो गये। यह वह समय था, जब आर्थिक दबाव उनकी जिंदगी से

आज की राजनीति काजल की कोठरी है और उसमें दामन बचाकर तमाम उम्र गुजारना मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की गाथा राजनीति के विभिन्न मोर्चों पर चल रहे अंतहीन महाभारत की अकेली कथा नहीं है। और भी हैं...

अरुण वोरा

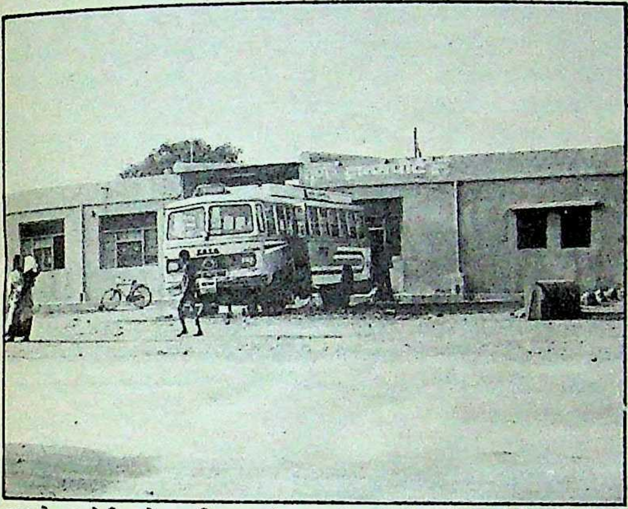

सत्ता के सहारे? : वोरा परिवार की एक और कंपनी दुर्ग ट्रांसपोर्ट

अरविंद वोरा

गुरदीप सिंह गरचा

मुकेश व्यास

लाभ ही लाभ: रायपुर ट्रांसपोर्ट की सजीधजी बसें

लिपटे हुए थे। इसी के चलते उन्हें अपने कुछ शेयर बेचने भी पड़े। २८ जून, १९६३ से २९ अप्रैल, १९७१ तक वोरा दुर्ग रोडवेज में डायरेक्टर रहे और ३० अप्रैल, १९७१ को उन्होंने इसी कंपनी में प्रबंध संचालक का पद संभाला।

'वोराजी बहुत कम काल के लिये एमडी (प्रबंध संचालक) बने'—दुर्ग रोडवेज प्रालि के वर्तमान एमडी निर्मल सिंह बल बताते हैं, "वे करीब सवा साल एमडी रहे। उनके पहले हमारे पास २८ बसें थीं और १९ परमिट। इसके बाद बसों और परमिटों की संख्या घटती-बढ़ती रही। १९७९ में बसों और परमिटों की संख्या क्रमशः ३७ और ३२ हो गयी। १९८३ अर्थात अर्जुन सिंह के प्रथम मुख्यमंत्रित्व-काल के अंत में कंपनी के पास ३६ परमिट और ४६ बसें हो गयी थीं। तदुपरांत मार्च, १९८५ में मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। १९८५ से १९८८ की अवधि में कंपनी की बसों के बेड़े में दहाई की वृद्धि हुई। आज कंपनी के पास दो मिनी बसों समेत कुल ५६ बसें हैं।

विवाद : दुर्ग रोडवेज को मिले परमिटों ने उसके समेत अनेक ट्रांसपोर्ट कंपनियों और साथ ही सरकार को लंबे विवाद एवं अदालती व अखबारी लड़ाई में उलझा दिया है। १९८७ में एमपी ट्रांसपोर्ट के दो परमिटों के हस्तांतरण के कारण दुर्ग रोडवेज के परमिटों की संख्या ३८ हो गयी थी। इस बीच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर एएन तिवारी का आगमन हो चुका था। एएन तिवारी वोरा-भक्त नौकरशाह माने जाते हैं और एक खेमे का खुला प्रचार व आरोप है कि प्रतिनियुक्ति देकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से की गयी थी। बहरहाल, इसे अधिकार कहें, पात्रता कहें या लंबे हाथों का नतीजा कि १९८७ में दुर्ग रोडवेज को पांच परमिट मिले। कंपनी को एकमुश्त पांच परमिट मिलने की घटना और फिर महेंद्रा बस सर्विस और छत्तीसगढ़ परिवहन की आपत्तियों और चुनौतियों ने न केवल मामला खटाई में डाल दिया, वरन् ट्रांसपोर्ट कंपनियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को खुली लड़ाई में बदलकर उसी आग को और भड़का दिया।

छग परिवहन नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी कुछ साल पहले तक रायपुर ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा थी। जगमीर सिंह गरचा के स्वामित्व की इस कंपनी के बारे में खास बात यह है कि ये कंपनी पंद्रह ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सदस्यतावाले छत्तीसगढ़ यातायात संघ की सदस्य नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बीच जारी लड़ाई में महेंद्रा बस सर्विस छग परिवहन की सहयोगी है। जगमीर के भतीजे सतवंत सिंह गिल इसके मालिक हैं। बेमेतरा, मुंगेली, दाढ़ी, नवागांव, नांदघाट, भाटापारा, रायपुर, बलौदा बाजार, बलौदा, सिमगा आदि मार्गों पर इन कंपनियों की बसें चला करती हैं।

दुर्ग रोडवेज को जिन रूटों के परमिट मिलने पर विवाद हुआ और जिसे छग परिवहन ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी, वे रूट हैं—साजा-कोठरा, रायपुर-खमरिया, दुर्ग-बिम्होरी, दुर्ग-बेमेतरा और बड़ागांव—दुर्ग। बताते हैं कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के समक्ष परमिटों के लिए कुल २१ अर्जियां आयी थीं। तमाम अर्जियों को निरस्त कर कुल आठ परमिट दिये गये, जिनमें से पांच दुर्ग रोडवेज, दो दुर्ग ट्रेवेल्स और एक अन्य को मिला। सतवंत ने अपनी याचिका में आरटीए, रायपुर और दुर्ग रोडवेज के अलावा मोतीलाल वोरा को भी प्रतिवादी बनाया है। जब यह याचिका दाखिल की गयी तब वोरा केंद्र सरकार में स्वास्थ्यमंत्री थे।

सतवंत मानते हैं कि क्षेत्रीय परिवहन

अधिकारी ने वोरा परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ पक्षपात और उनके साथ भेदभाव किया। जगमीर और दुर्ग जिला मजदूर कामगार कोआपरेटिव सोसायटी के एके शुक्लं सतवंत की बातों को सही ठहराते हैं। इस सोसायटी के पास ग्यारह बसें हैं और वे छग यातायात संघ से नाता तोड़नेवालों की कतार में शरीक हैं।

पुत्र और पत्नी : वोरा परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के तौर पर दुर्ग रोडवेज के अलावा दुर्ग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रालि और दुर्ग ट्रेवेल्स प्रालि के नाम लिये जाते हैं। १९७२ में वोरा ने करीब पंद्रह माह एमडी पद पर कार्य करने के बाद दुर्ग रोडवेज से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कंपनी से उनका नाता नहीं टूटा था। ३० जून, १९७३ से २७ जून, १९७६ तक वोरा की पत्नी श्रीमती शाति वोरा कंपनी की डायरेक्टर रहीं। २८ जुलाई, १९७६ को संचालक मंडल की बैठक में मोतीलाल वोरा फिर संचालक चुने गये और जून, १९८१ में इस पद से इस्तीफा देने और अपने ४१ शेयर अपने बड़े बेटे अरविंद वोरा को 'गिफ्ट' करने के बाद उन्होंने कंपनी से पूरी तौर पर किनारा कर लिया। फिलहाल, दुर्ग रोडवेज के ३७ अंशधारियों में से अरविंद वोरा भी एक हैं, किंतु कंपनी के तेरह डायरेक्टरों में उनका नाम समाविष्ट नहीं है। अरविंद के ४१ शेयरों के अलावा दुर्ग रोडवेज से वोरा परिवार का फिलहाल कोई संबंध नहीं है।

अरविंद के अनुज और मुख्यमंत्री के छोटे बेटे का नाम है, अरुण वोरा। अरुण को सामान्यत: मोतीलाल वोरा का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के अतिरिक्त वे दुर्ग जिला युवक कांग्रेस-इ के अध्यक्ष भी हैं। दुर्ग की दो ट्रांसपोर्ट कंपनियों—दुर्ग ट्रांसपोर्ट और दुर्ग ट्रेवेल्स में उनके शेयर हैं। आम तौर पर अरुण के शेयरों की संख्या काफी ज्यादा बतायी जाती है, किंतु उपरोक्त कंपनियों के प्रबंध संचालकों के अनुसार, अरुण के पास दुर्ग ट्रेवेल्स में सौ-सौ रुपए के एक सौ और दुर्ग ट्रांसपोर्ट में मात्र छह (प्रत्येक पांच सौ रुपए के) शेयर हैं।

इसी क्रम में अरविंद वोरा से 'माया' संवाददाता की भेंट दुर्ग में मोहन नगर स्थित उनके आवास पर हुई। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा, "मुझे तो पता नहीं कि कितने शेयर मेरे पास हैं और कितने बाबू के पास।" बाबू से उनका तात्पर्य अपने छोटे भाई अरुण से था। उन्होंने आगे कहा, "आप मुझसे पूछें कि कंपनी के पास कितनी बसें हैं और वे किन रूटों पर चलती हैं, तो मैं आपको नहीं बता सकता। पिताजी ने बहुत पहले शेयर खरीदे थे और मंत्री बनने पर हम लोगों को ट्रांसफर कर दिये।"

आरोप : आज दुर्ग की उपरोक्त तीनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लेकर मुख्यमंत्री वोरा गंभीर आरोपों से बिंधे हुए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इन कंपनियों के व्यावसायिक हितों के लिए सरकारी हितों को बलाएताक रख दिया। प्रसंग इस प्रकार है—लगभग पांच साल पहलें एएन सिंह परिवहन आयुक्त थे। अर्जुन सिंह तब मुख्यमंत्री थे। परिवहन आयुक्त ने यात्री-कर में वृद्धि का एक प्रस्ताव तैयार किया। इस बीच अर्जुन सिंह की जगह वोरा मुख्यमंत्री बन गये। जून, १९८५ में जैसाकि प्रचारित किया गया है, वोरा ने एएन सिंह की छुट्टी कर दी और उनकी जगह रामरतन को परिवहन आयुक्त बना दिया। रामरतन ने आते ही पहला काम यह किया कि अपने पूर्ववर्ती आयुक्त महोदय के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। गृह एवं परिवहन विभाग से इस संबंध में 'माया' को मिली जानकारी के अनुसार एएन सिंह को वोरा ने तीन माह नहीं, बल्कि एक साल बाद मई, १९८६

शुक्ल परिवार और एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी

श्रीमती पद्मिनी शुक्ल

श्यामाचरण शुक्ल

प्रह्लाद आहुजा

यह कदाचित संयोग है कि विगत दो दशकों में छत्तीसगढ़ अंचल ने मध्य प्रदेश को दो ऐसे मुख्यमंत्री दिये, जिन्हें दो-दो बार प्रदेश की बागडोर संभालने का गौरव मिला। यह भी मजेदार संयोग है कि ये दोनों ही राजनेता (श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा) ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़े हुए हैं।

रायपुर स्थित एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा०लि० से श्यामाचरण का इस नाते सीधा रिश्ता है कि उनकी पत्नी श्रीमती पद्मिनी शुक्ल इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। श्रीमती शुक्ल के पास इस कंपनी के सर्वाधिक लगभग ३० प्रतिशत शेयर हैं। इस कंपनी के अन्य अंशधारी एवं संचालक मंडल के सदस्य है: प्रह्लाद राय आहुजा, डा० ईश्वरीचरण शुक्ल, गिरजाचरण शुक्ल और बरंकत अली फरिश्ता। डा० ईश्वरीचरण और गिरजाचरण श्यामाचरण के सगे भाई हैं और क्रमशः नागपुर एवं जबलपुर में रहते हैं।

१२ अप्रैल, १९५५ को स्थापित इस कंपनी की बसें रायपुर से राजिम, फिंगेश्वर, महासमुंद, गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग तिल्दा, खरोरा आदि स्थानों के बीच दौड़ती हैं। कंपनी का एक डिपो बिलासपुर में है और वहां से कंपनी की बसें कोरबा, पंडरिया, अंबिकापुर तथा पंडरिया से कोरबा व दुर्ग को जाती हैं।

प्रह्लाद राय आहुजा १९८२ से कंपनी के संचालक तथा अप्रैल, १९८६ से प्रबंध संचालक हैं। राजनीति में शुक्ल-परिवार के लंबे वर्चस्व के कारण इस कंपनी को वीआईपी ट्रांसपोर्ट कंपनी माना जाता रहा है। किंतु प्रह्लाद राय आहुजा इससे इनकार करते हैं और मानते हैं कि राजनेताओं के पारस्परिक संबंधों का खमियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा है। स्कीम नंबर-८३ को वे इसका प्रमाण निरूपित करते हैं। स्कीम नंबर ८३ सन् १९८३ में सामने आयी थी और इसके जरिये रायपुर से राजिम, फिंगेश्वर, महासमुंद्र, गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग, तिल्दा और खरोरा के मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। स्कीम के लागू होने का अर्थ था, एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी का भट्टा बैठना, क्योंकि इन रूटों पर उसकी बसें दौड़ा करती थीं। आहुजा बताते हैं, "हमने आपत्ति उठायी, तो विशेष सचिव, गृह एवं परिवहन चंद्रा ने हमारी अपील केवल एक दिन की सुनवाई में निरस्त कर दी। विवश होकर हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मार्च, १९८४ में हमें वहां से स्थगन मिल गया। इस पर मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी और समानांतर चालन के लिये

में हटाया।

उपरोक्त प्रसंग आज वोरा-विरोधियों के हाथों में वोरा को बदनाम करने का सबसे बड़ा हथियार है। उनका कहना है कि उन्होंने निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लाभ के लिए आयुक्त के कर-वृद्धि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एएन सिंह ने यात्री-कर की दर को १२ पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दस किमी से बढ़ाकर १८ पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दस किमी करने का प्रस्ताव किया था। वोरा ने इस प्रस्ताव पर काबीने में चुप्पी साध ली है और परिवहन आयुक्त का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

निलंबन और नियुक्तियां: आरटीओ कुरैशी का निलंबन प्रसंग ट्रांसपोर्ट-गाथा में क्षेपक की भांति जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्रियों से जुड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की विरोधी लाबी कुरैशी के निलंबन को दुर्ग रोडवेज की कारस्तानी इस नाते मानती हैं, क्योंकि कुरैशी ने दुर्ग रोडवेज की दुर्ग-चंदन की परमिट की अर्जी ठुकरा दी थी। इसके अतिरिक्त, वे नये परमिटों के लिए छग का व्यापक सर्वेक्षण करने के भी मूड में थे। पता चला है कि कुरैशी के खिलाफ दुर्ग रोडवेज के एमडी निर्मल सिंह बल ने एक शिकायतनामा भी लोकायुक्त को भेजा था। इसके परिप्रेक्ष्य में कुरैशी को ३ मार्च '८९ को निलंबित किया गया। इस पर कुरैशी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की शरण में गये, जहां ९ मार्च '८९ को उन्हें राहत मिली और वे बहाल हुए।

वोरा ने हमारे लिए क्या किया? : निर्मल सिंह बल

वस्तुस्थिति: वोरा-विरोधियों की दलील में 'अगर' का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता, तो १९८५ से १९८९ की अवधि में शासन को ६३ करोड़ रुपए की आय होती। वे कहते हैं कि वोरा के ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मोह के कारण शासन ६३ करोड़ रु० की आय से वंचित रहा और इस राशि का एक बड़ा अंश वोरा-परिवार की मोटर कंपनियों के खाते में गया।

"यह तर्क कुछ ऐसा ही है कि अगर फलां साल बच्चा पैदा हो जाता, तो अब तक बड़ा होकर दौलत का अंबार लगा देता", वोरा परिवार के एक नजदीकी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने चुटकी ली। दुर्ग ट्रांसपोर्ट के एमडी प्रकाश देशलहरा ने कहा, "कैसे कह सकते हैं कि करोड़ों की रकम का एक बड़ा हिस्सा वोरा परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पास गया?" चाहे देशलहरा हों या दुर्ग रोडवेज के एमडी निर्मल सिंह बल, दोनों को इस बात पर सख्त एतराज है कि तीनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों को वोरा परिवार की मिल्कीयत कहा जाये। वे कहते हैं, "वोरा परिवार का कोई भी सदस्य हमारे संचालक-मंडल में नहीं है। अरविंद वोरा और अरुण वोरा मात्र शेयरधारी हैं और उनका भी इन कंपनियों के दैनंदिन कारोबार से कोई सरोकार नहीं है।" बल बताते हैं कि उनके एमडी-काल में तो वोरा एक बार भी कंपनी के दफ्तर में झांकने तक नहीं आये। प्रकाश देशलहरा कहते हैं कि उनकी तो बरसों से वोराजी से मुलाकात ही नहीं हुई है।

वोरा के काल में लाभ नहीं मिला: प्रकाश देशलहरा

वस्तुस्थिति जानने के प्रयोजन से 'माया' ने जब मुख्यमंत्री वोरा से संपर्क किया, तो बल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल पर अपने कक्ष में उन्होंने कहा, "यह कहना सरासर गलत है कि मैंने परिवहन आयुक्त का प्रस्ताव ठुकराया। प्रस्ताव न तो काबीने की बैठक में प्रस्तुत हुआ और न ही मेरे समक्ष आया। (देखिये साक्षात्कार) वोरा के कथन की पुष्टि करते हुए गृह एवं परिवहन विभाग के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव मुख्यमंत्री तक पहुंचा ही नहीं था। तो क्या वोरा का यह कथन सही है कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। वोरा कहते हैं, "कुछ लोग मेरी छवि विकृत करने के षड्यंत्र में लिप्त हैं।"

एएन सिंह के प्रस्ताव के मुख्यमंत्री अथवा काबीने के समक्ष न आने से मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दुर्ग की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लाभ पहुंचाने का लांछन नहीं लगाया जा सकता, किंतु वोरा ने जाने-अनजाने कुछ ऐसे कदम अवश्य उठाये हैं, जो संदेह की सुई में कंपन पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, दुर्ग के अधिवक्ता बजरंगलाल जोशी को राज्य परिवहन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया गया। इसी क्रम में, चार दिनों बाद दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके चावला को ७ जुलाई '८९ को मप्र राजपत्र की एतद्विषयक घोषणा से स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया। इससे और कुछ हो या नहीं, लेकिन लोगों को इन नियुक्तियों को शक-शुबहे से देखने और नाहक उंगलियां उठाने का मौका मिल गया।

पक्ष-प्रतिपक्ष: 'द रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रालि' मध्य प्रदेश की पुरानी और नामीगिरामी कंपनी है। आज इस कंपनी की ४२ बसें रायपुर से भानसोज, चंदखुरी, टीला, गिधपुरी, भकारा, कसडोल, राजनांदगांव से कवर्धा, कवर्धा से दुर्ग, बैहर और सालेवाड़ा के ऊबड़खाबड़ मार्गों पर दौड़ती हैं। इसके प्रबंध संचालक हैं—गुरदीप सिंह गरचा और मुकेश व्यास जो छग यातायात संघ के सेक्रेट्री भी हैं। प्रीतम सिंह गरचा, प्रभुलाल व्यास, जयसुखलाल दवे, विक्रमजीत शारदा और मनजीत सिंह इसके संचालक मंडल के सदस्य हैं। एएन सिंह के बहुचर्चित प्रस्ताव का हवाला देते हुए व्यास और गरचा ने कहा, "आज की तारीख में १८ पैसे 'कर' देने की क्षमता किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरे प्रदेशों की स्थितियों को ध्यान में रखकर यह अव्यवहारिक प्रस्ताव तैयार किया था।" युवा एमडी द्वय ट्रांसपोर्ट कंपनियों को करोड़ों रुपए का लाभ होने की बात को भी काल्पनिक और अतिरंजित निरूपित करते हैं। उनके अनुसार, परमिटों का ट्रांसफर कोई अवैधानिक बात नहीं है। कंपनियों द्वारा एक दूसरे को परमिट ट्रांसफर करने का सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। दुर्ग और रायपुर की चर्चित कंपनियों के अलावा सिहावा रोडवेज और धमतरी-राजनांदगांव रोडवेज जैसी कंपनियों ने भी अपने परमिट

वहां से स्थगन प्राप्त कर लिया। अब स्थिति यह है कि इन मार्गों पर एमपी ट्रांसपोर्ट और रापनि दोनों की बसें चल रही हैं। रापनि हमारी बसों से पंद्रह-पंद्रह मिनट पहले बसें छोड़ता है। इससे उनके मकसद और हमारी कमाई पर पड़े असर का आप अंदाजा लगा सकते हैं।"

छग परिवहन समेत कुछ कंपनियों को जिस प्रकार मोतीलाल वोरा से शिकायत है, एमपी ट्रांसपोर्ट को उसी प्रकार अर्जुन सिंह से। आहुजा कहते हैं, "अर्जुन सिंह के काल में हमें परमिटों के नवीनीकरण में दिक्कतें आयीं। हमारा बिलासपुर-कोरबा-पंडरिया का परमिट निरस्त कर दिया गया, जिसे हमने अंततः स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल से हासिल किया। प्रताड़ना का भी दौर चला। हमारी बसों की कहीं भी चेकिंग कर जब्ती की घटनाएं बढ़ीं, तो हम उच्च न्यायालय गये और वहां से स्टे लेकर आये। स्टे के बाद इन घटनाओं पर अंकुश लगा।"

एमपी ट्रांसपोर्ट का दुर्ग रोडवेज या दुर्ग ट्रांसपोर्ट से कोई विशेष रिश्ता नहीं है। दोनों के बीच संबंधों की डोर बस इतनी है कि सन् १९८७ में एमपी ट्रांसपोर्ट ने दुर्ग रोडवेज को दो परमिट ट्रांसफर किये थे। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि एमपी ट्रांसपोर्ट के पूर्व एमडी तुलजाराम फतनानी संप्रति दुर्ग ट्रांसपोर्ट के संचालक मंडल के सदस्य हैं।

—सुधीर

हस्तांतरित किये हैं। दूसरे, अस्थायी और स्थायी परमिटों पर टैक्स में भी कोई अंतर नहीं है। व्यास के शब्दों में, "बड़ी बात यह है कि हममें से किसी ने भी किसी बेनामी कंपनी को परमिट ट्रांसफर नहीं किये। सतवंत और जगमीर यातायात संघ की मोनोपोली(एकाधिकार)की बात कहते हैं।औरों के साथ-साथ आनंद रोडवेज को भी परमिट मिला है जो संघ की सदस्य नहीं है।" व्यास के अनुसार छग में कुछेक रूटों पर छग परिवहन की मोनोपोली है। इन रूटों पर दसेक साल से किसी और कंपनी को परमिट नहीं मिला है। हम गंदी प्रतियोगिता और गलाकाट प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते हैं। इसलिए हममें से किसी ने इन रूटों के लिए कभी अर्जी भी नहीं लगायी। छग परिवहन बिना परमिट बसें चलाने में छग में अग्रणी है।" वोरा की छत्रछाया से इनकार करते हुए एमडी द्वय ने 'माया' से कहा, "हमारा राजनीति या वोरा से क्या सरोकार? वोरा तो दूर, अगर किसी बड़े मंत्री का भी हमारी पीठ पर हाथ होता, तो हमारे तीन-तीन साल पुराने परमिट निरस्त नहीं होते।"

लगभग इसी तरह की बातें दुर्ग में प्रकाश देशलहरा ने कीं। प्रकाश ने 'माया' से कहा, "वोरा के काल में लाभ तो दूर 'दुर्ग से महामाया' के रूट की हमारी अर्जी जरूर निरस्त हो गयी। हमारी अर्जी अस्वीकार कर इस रूट पर गुरु घासीदास कंपनी और जनता ट्रांसपोर्ट को परमिट दिये गये, जबकि हम कोर्ट से स्टे लेकर आये थे।" उन्होंने आगे कहा, "पत्र-पत्रिकाओं में छपी ऊलजलूल खबरों पर मैं हैरान हूं। हमारी बसों की संख्या बढ़ाचढ़ाकर बतायी गयी है। बेमेतरा-खैरागढ़ मार्ग पर दुर्ग ट्रांसपोर्ट ने कभी आपरेट नहीं किया। बेमेतरा-महामाया मार्ग पर तुलजाराम फतनानी (पहले एमपी ट्रांसपोर्ट के एमडी और अब दुर्ग ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर) ने बसें किराये पर लेकर दो माह जरूर चलायी थीं।"

लगभग इसी सुर और लहजे में बल ने कहा, "हमने एक भी बस बगैर परमिट नहीं चलायी। न ही परमिट किसी बेनामी कंपनी को ट्रांसफर किये। कथित नौ कंपनियों से दुर्ग रोडवेज का कोई संबंध नहीं है। हमारा कारोबार अलग—उनके मालिक, उनका कारोबार अलग।" वोरा से शिकायत बल को भी है। तभी वे कहते हैं, "ठीक है कि वोराजी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमें कौन-सी छूट दे दी या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट दिला दिये? हाल की बात बताऊं। २६ मई, १९८९ को हमने रायपुर—बालाघाट बरास्ते बैहर, मलाजखंड, बालाघाट—दुर्ग बरास्ते बैहर, सालोमी और मंडला-दुर्ग बरास्ते चिरईडोंगी परमिट के लिए अर्जियां लगायीं। २१ जुलाई, १९८९ को हमारी ये तीनों अर्जियां निरस्त कर दी गयीं।"

किराया वृद्धि: पिछले लगभग एक दशक में बसों के किराये में अनापशनाप वृद्धि हुई है। १९७८ से १९८९ के बीच बसों के यात्री—किराये में तकरीबन ११८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। १ अगस्त, १९७८ को जनता काल में किराया वृद्धि के बाद १५ जनवरी, १९८३ को अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में और फिर ४ जुलाई, १९८५ को वोरा के काल में किराये में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ११८ प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रतिकूल असर यात्रियों की जेब पर पड़ा और अनुकूल असर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुनाफे पर। इससे निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने तगड़ा मुनाफ़ा कमाया, लेकिन सरकार ने किराये में वृद्धि की क्यों?

निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिकों से लेकर मप्र शासन के परिवहन विभाग के अधिकारी तक इस बात पर एकमत हैं कि किराये में वृद्धि हमेशा मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के आग्रह पर हुई। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की इसमें कभी कोई भूमिका नहीं रही। बरसों से रापनि भारीभरकम घाटे का शिकार है और उसमें करों के भुगतान की भी सामर्थ्य नहीं है। इससे उबरने के लिये जब-तब उसके आग्रह पर राज्य सरकार ने किराये बढ़ाये। सही बात यह है कि अगर किराये के साथ ही यात्रीकर भी बढ़ाया जाता, तो किराया-वृद्धि का कदम बेमानी हो जाता। तो क्या एएन सिंह का प्रस्ताव मानने पर सर्वाधिक बोझ

मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम

सफेद हाथी : कहि न जाये, का कहिये

मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम (मप्र रापनि) की महिमा अनंत है। रापनि के साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा १९७१ में राज्य विधान सभा के लिए पहली बार चुने जाने के बाद सन् १९७२ में रापनि के उपाध्यक्ष बनाये गये थे और यहीं से वोरा के कुर्सियों के खेल में शरीक होने की कहानी शुरू होती है।

मप्र विद्युत मंडल के बाद रापनि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है। इसके कर्मचारियों की संख्या करीब २२ हजार है और इसके पास करीब तीन हजार बसों का काफिला है। इन कलगियों और तुर्रों को छोड़ दें, तो रापनि सही मायनों में असली सफेद हाथी है। इसकी दुर्दशा और व्याप्त अनियमितताओं की कथा इसके रजत-जयंती वर्ष में 'माया' में विस्तार से छप चुकी है, किंतु कुछ ताजा प्रसंग उल्लेखनीय हैं। मप्र में करीब एक दशक में ११८ प्रतिशत यात्री किराया वृद्धि के लिए और कोई नहीं, इकलौता रापनि जिम्मेदार है, किंतु इसमें व्याप्त अनियमितताओं का दायरा इतना बड़ा है कि जनवरी, १९८९ तक इसका घाटा एक अरब, १७ करोड रुपए को लांघ चुका था। केवल १९८८-८९ में ही इसने १३ करोड़ रुपए का घाटा अर्जित किया। यह सफेद हाथी अपनी खुराक के लिए फिलवक्त ऋण-सहायता एवं अनुदान पर जी रहा है। लिहाजा, उसे हर माह करीब ६० लाख रुपए अर्थात प्रतिदिन दो लाख रुपए का भुगतान ब्याज के मद में करना पड़ता है।

रापनि के चेयरमैन और एमडी में चले द्वंद्व की कथाएं आज भी लोग भूले नहीं हैं। मलिक बनाम जैन के द्वंद्व का समापन अंततः दोनों के पलायन में हुआ। हालांकि, वोरा के चहेते विजय कुमार पाटनी सजातीय जैन को निगम में एमडी बनाये रखना चाहते थे, किंतु इस मुहीम में उनके पासे उलटे पड़े। हताश हिटलर यानी पाटनी ने यह भी जुगत भिड़ाई कि जैन टीकमगढ़ में कलेक्टर हो जायें, किंतु यहां भी उनकी दाल नहीं गली और जैन को बाध्य होकर शिक्षा विभाग में जाना पड़ा।

विजय कुमार पाटनी

विजय कुमार पाटनी के सफेद हाथी का महावत बनने से उम्मीद बंधी थी कि निगम के बिगड़े ढर्रे में सुधार होगा। इसी के तहत ३७७ कर्मियों की छंटनी की गयी थी। आश्चर्य है कि इधर कुछ नयी नियुक्तियां हुई हैं। दुबले पर दो आषाढ़ की तर्ज पर निगम के आकस्मिक यानी कंटिन्जेन्सी मद में इस साल गत वर्ष की अपेक्षा ४० लाख रुपए का अधिक व्यय हुआ है। इधर ईंधन की प्रति किमी खपत भी बढ़ी है। हालांकि निगम के घाटे का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन निगम ने अपनी साख बनाये रखने के लिए हाल में चेयरमैन के लिए नयी कंटेसा गाड़ी खरीदी है। वातानुकूलित कंटेसा के अलावा रापनि ने चेयरमैन की चाकरी में मारुति वैन और अम्बेस्डर कार भी लगा रखी हैं।

—एसपी त्रिपाठी

सीदास
ये गये,
उन्होंने
जलूल
संख्या
बैरागढ़
किया।
तनानी
सब दुर्ग
र लेकर

ने कहा,
यी। न
ट्रांसफर
का कोई
—उनके
ीरा से
'ठीक है
हमारे
दी या
? हाल
हमने
राजखंड,
ी और
के लिए
हमारी

क दशक
हुई है।
-किराये
हुई है।
कराया
नि सिंह
जुलाई,
लेखनीय
द्धि का
ा और
फे पर।
मुनाफ़ा
द्धि की

नकों में
ाग के
किराये
निगम के
ी इसमें
रापनि
करों के
रने के
कार ने
किराये
ता, तो
तो क्या
क बोझ

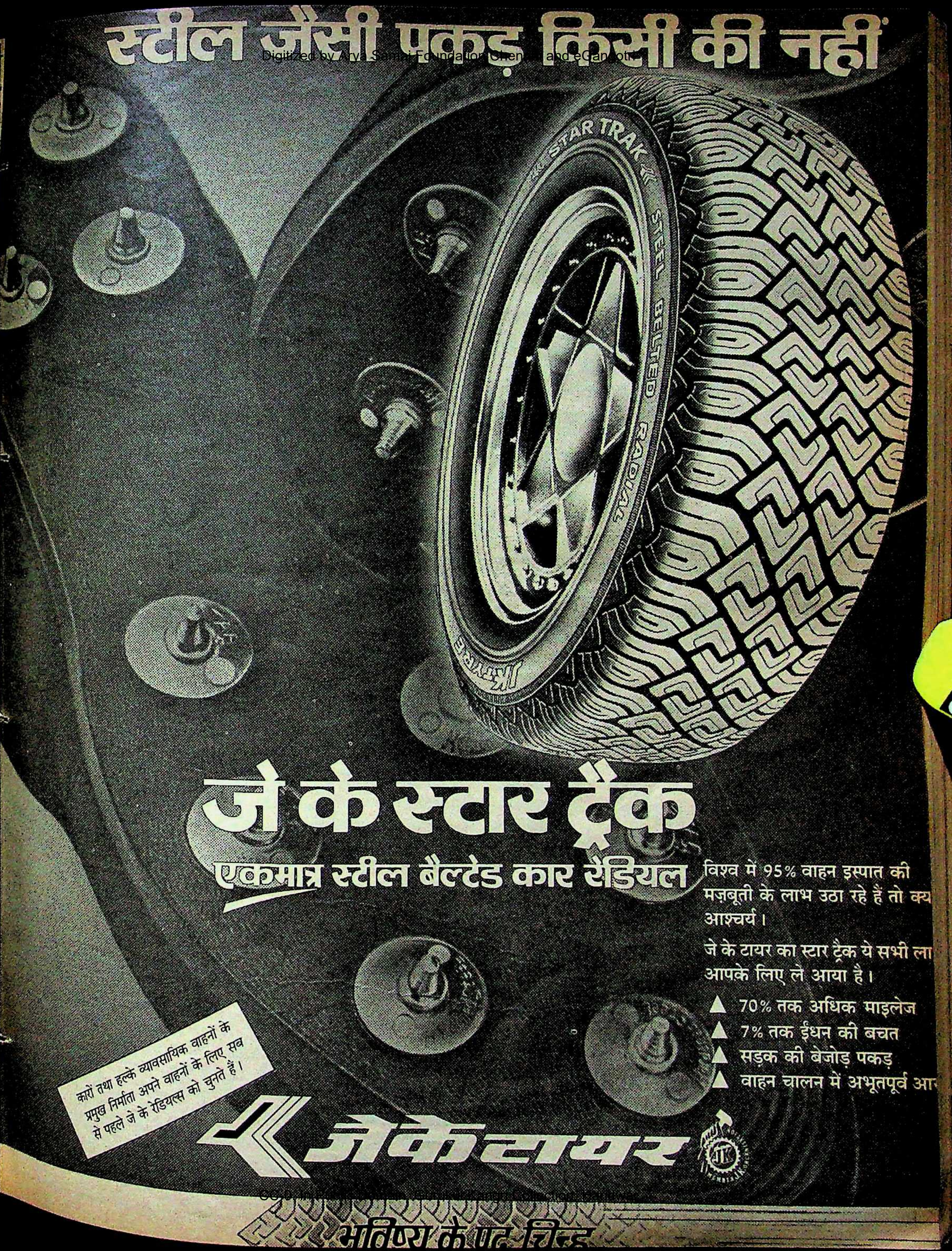

स्टील जैसी पकड़ किसी की नहीं

जे के स्टार ट्रैक

एकमात्र स्टील बैल्टेड कार रेडियल

विश्व में 95% वाहन इस्पात की मज़बूती के लाभ उठा रहे हैं तो क्य आश्चर्य।

जे के टायर का स्टार ट्रैक ये सभी ला आपके लिए ले आया है।

- ▲ 70% तक अधिक माइलेज
- ▲ 7% तक ईंधन की बचत
- ▲ सड़क की बेजोड़ पकड़
- ▲ वाहन चालन में अभूतपूर्व आ

कारों तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों के प्रमुख निर्माता अपने वाहनों के लिए सब से पहले जे के रेडियल्स को चुनते हैं।

जेकेटायर

भविष्य के पद चिह्न

निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिकों से लेकर मप्र शासन के परिवहन विभाग के अधिकारी तक इस बात पर एकमत हैं कि किराये में वृद्धि हमेशा मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (रापनि) के आग्रह पर हुई। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की इसमें कभी कोई भूमिका नहीं रही। बरसों से रापनि भारीभरकम घाटे का शिकार है और उसमें करों के भुगतान की भी सामर्थ्य नहीं है।

निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बजाय मप्र रापनि के कंधों पर आता? शायद हां, क्योंकि रापनि के पास सबसे विशाल—करीब तीन हजार बसों का—रेवड़ है। (देखें बाक्स)

राजनीति: आज के बेढब समय में राजनीति से दामन बचाना हरेक के लिये मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां इसकी अपवाद नहीं हैं। वोरा ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लाभ पहुंचाने से इनकार कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से संबद्धता से नहीं। वोरा अकेले ऐसे राजनेता नहीं हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। श्यामाचरण शुक्ल का एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी से सीधा और प्रगाढ़ रिश्ता है। उनके गर्दिश के दिनों में एमपी ट्रांसपोर्ट ने भी परेशानियां झेलीं। (देखें बाक्स) वस्तुतः ट्रांसपोर्ट कंपनियां चाहने पर भी राजनीति के दंश से बच नहीं सकी हैं। जनता काल में कांग्रेसी नेताओं की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सुगबुगाहट जरूर थी, किंतु किराया वृद्धि को छोड़ और कुछ करने के पहले ही जनता सरकार विदा हो गयी। कांग्रेस के पुनर्सत्तारोहण के बाद करीब तीन साल तक माहौल ठंडा रहा। १९८३ में फिर किराये बढ़े और कुछ रूटों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण से क्षुब्ध होकर एमपी ट्रांसपोर्ट ने अदालत के द्वारा खटखटाये। १९८५ में विधानसभा चुनाव के बाद अगर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने रहते, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों की, बहुत संभव है, शामत आ जाती। मगर वोरा के मुख्यमंत्री बनने से खतरा टल गया। वोरा ने भला भले ही नहीं किया हो, मगर बुरा भी नहीं किया। फरवरी, १९८८ में अर्जुन सिंह दुबारा मुख्यमंत्री बने और छमाही बीतने के पहले ही टैक्स बढ़ गये। पहले ट्रांसपोर्ट कंपनियों को पावस में ८ पैसे कच्चे और ९ पैसे पक्के का तथा सीजन में १० पैसे कच्चे और १२ पैसे पक्के का टैक्स देना पड़ता था। जुलाई, १९८८ में ९ पैसे पावस और १२ पैसे सीजन की फ्लैट रेट लागू हो गयी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने इसे अपने हितों पर पहला कुठाराघात माना। अगले वर्ष १९८९ में अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के एक दिन पहले अध्यादेश जारी हुआ और कच्चे-पक्के के बाद पावस और सीजन का भेद मिटाकर १६ पैसे का बारहमासी रेट लागू हो गया। इस रेट के लागू होने से उत्पन्न बेचैनी और अकुलाहट निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिकों में आज भी देखी जा सकती है।

आज की राजनीति काजल की कोठरी है और उसमें दामन बचाकर तमाम उम्र गुजारना मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की गाथा राजनीति के विभिन्न मोर्चों पर चल रहे अंतहीन महाभारत की अकेली कथा नहीं है। किस्से और भी हैं, परंतु इससे कौन इनकार करेगा कि सत्य जहां प्रकाश-पुंज और अजस्र ऊष्मा उत्पन्न करता है, वहीं तथ्यविमुख आधा-अधूरा सच धुंध पैदा करता है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों और उनसे जुड़े पात्रों की कथा का उपसंहार संभवतः इसी तथ्य को उद्घाटित करता है।

—सुधीर सक्सेना, रायपुर और दुर्ग से।

साक्षात्कार: मोतीलाल वोरा

'आयुक्त का प्रस्ताव मेरे समक्ष नहीं आया'

माया: ***क्या यह सही है कि आप प्रदेश में निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों अथवा ट्रांसपोर्ट लाबी से जुड़े हुए हैं और उनके हितों को संरक्षण देते रहे हैं?***

वोरा: *मैं नहीं जानता कि प्रदेश में ऐसी कोई लाबी है या नहीं, लेकिन आपका अभिप्राय जिनसे है, मैंने उनके हितों को संरक्षण कभी नहीं दिया। मैंने सदैव प्रदेश के हितों को सामने रखा है और व्यक्तिगत हितों को कभी महत्व नहीं दिया। मेरे जीवन का यह सतत और अटल उद्देश्य रहा है कि जिस किसी भी पद पर हैं, उसका लाभ न स्वयं लें और न ही परिवार के किसी सदस्य को लेने दें।*

माया: ***कहा जाता है कि पांच वर्ष पहले तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने यात्री कर को १२ पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दस किमी से बढ़ाकर १८ पैसे करने का प्रस्ताव भेजा था, किंतु ट्रांसपोर्ट कंपनियों के हितों के लिए जनता पर भार बढ़ने का तर्क देकर आपने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी सिलसिले में यह भी कहा जाता है कि इस कदम से शासन को १९८५ से १९८९ की अवधि में ६३ करोड़ रुपए की क्षति हुई। ये बातें कहां तक सही हैं?***

वोरा: *मेरे पास इस तरह का कोई प्रपोजल (प्रस्ताव) नहीं आया। यह कहना सरासर गलत है कि मेरे समक्ष प्रस्ताव आया और मैंने उसे ठुकराया। क्षति का आंकड़ा सर्वथा कपोलकल्पित है। जब प्रस्ताव मेरे पास आया ही नहीं और काबीने के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ, तो इस ६३ करोड़ रुपयों की गणना का भला क्या औचित्य?*

माया: ***आरोप है कि आपने सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की अवहेलना कर आठ प्रशासनिक अधिकारियों को परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्तियां दीं। इनमें सबसे प्रमुख नाम एएन तिवारी का लिया जाता है, जिन्हें आपने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बनाया...***

वोरा: *ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एएन तिवारी की पदस्थापना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं की गयी थी।*

माया: ***फिलहाल, दुर्ग की ट्रांसपोर्ट कंपनियों—दुर्ग रोडवेज और दुर्ग ट्रेवेल्स—से आपके क्या संबंध हैं?***

वोरा: *दोनों पुत्रों के शेयरों के अलावा इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। १९६३ में मैंने पांच-पांच सौ रुपए के ४५ शेयर लिये थे। १९७२ में विधायक बनने पर मैंने अपने शेयर लड़कों को ट्रांसफर कर दिये। १९७२ में मैं पहली बार विधायक बना, १९८० में मंत्री और फिर १९८५ में मुख्यमंत्री बना, मगर आप गौर करें कि ये बातें आज १९८९ में उठायी जा रही हैं। अगर गलतियां हुईं थीं, तो लोग इतने साल क्यों चुप रहे?*

माया: ***तो क्या यह किन्हीं न्यस्त स्वार्थों के दूरगामी उद्देश्य का कोई षड्यंत्र है?***

वोरा: *बिलकुल। कांच के मकान में रहनेवाले दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। इन बातों के पीछे न्यस्त स्वार्थी तत्व काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि वे कौन लोग हैं (आई नो देम परफेक्टली वैल) मैंने कोई गलती की होती, तो मैं बेहिचक स्वीकार कर लेता, लेकिन मैंने कहीं कोई गलत काम नहीं किया। ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़ा कोई व्यवसायी नहीं कह सकता कि मैंने उसे लाभ पहुंचाया या उसने वोराजी को 'फीड' किया। मैंने छवि का खयाल सदैव रखा है। अच्छी छवि कहने की बात नहीं होती। वह आचरण से उपजती है। प्रदेश की जनता मेरे आचरण से पूरी तरह परिचित है। उसे गुमराह नहीं किया जा सकता।*

—सुधीर सक्सेना

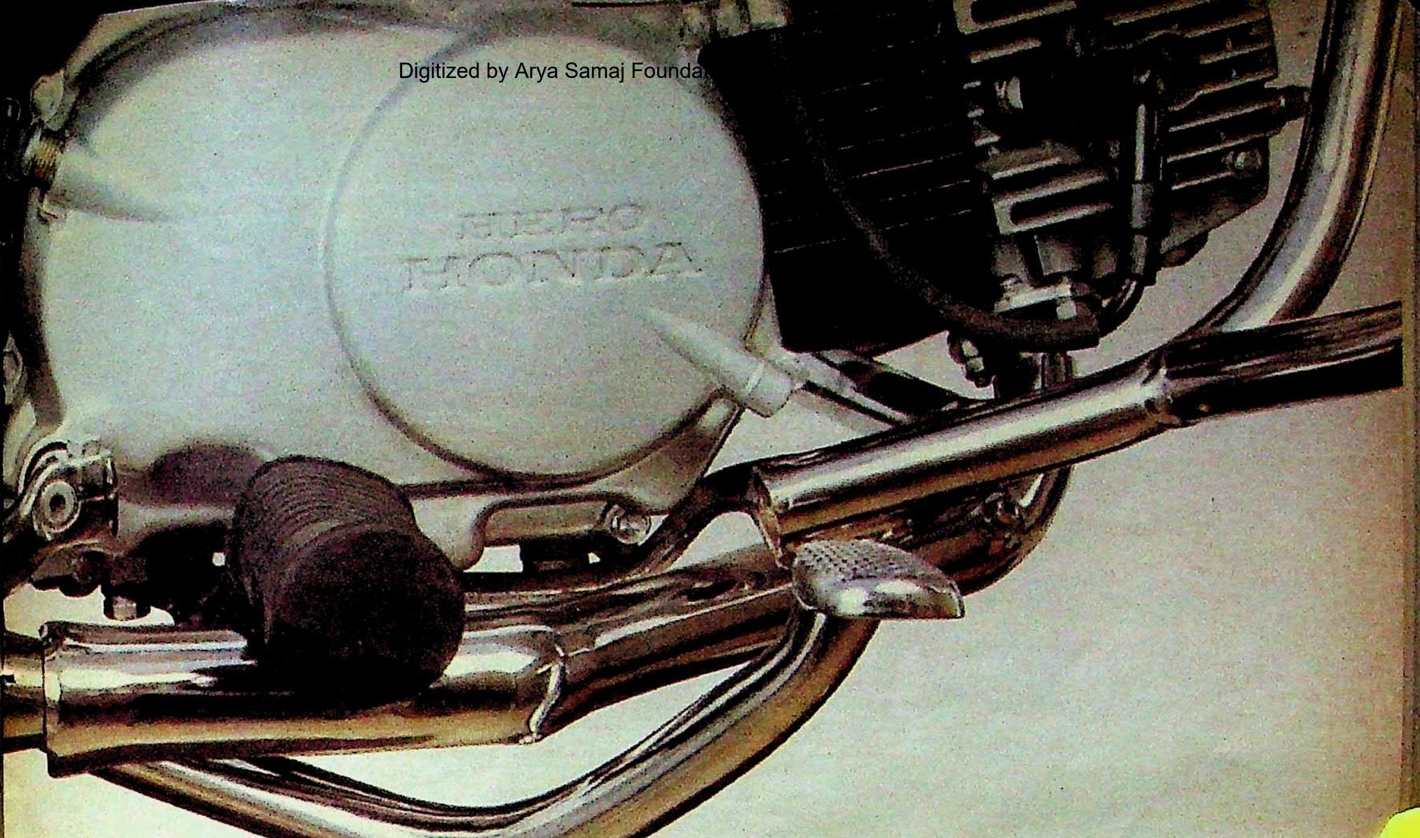

होन्डा की तकनॉलोजी से बना है यह हीरो.

हीरो होन्डा सी डी 100 की सफ़लता के पीछे विश्व के सर्वोच्च मोटरसाइकिल निर्माता होन्डा का योगदान है। होन्डा—जो डिज़ाइन के उच्चतम स्तरों तथा उत्तम इंजीनियरी के कारण दुनिया-भर में अग्रणी है।

4-स्ट्रोक इंजन के लाभ:
होन्डा की तकनीकी श्रेष्ठता हीरो होन्डा सी डी 100 के असाधारण 4-स्ट्रोक इंजन की हर विशेषता में देखी जा सकती है। ईंधन पूरी मात्रा में जलने के कारण देखभाल में आसानी, 80 किलोमीटर प्रति लीटर* चलने की कुशलता, और साथ में प्रदूषणहीन एग्ज़ास्ट सुनिश्चित हैं—मीलों मील बिना-परेशानी अच्छी सेवा के लिए।

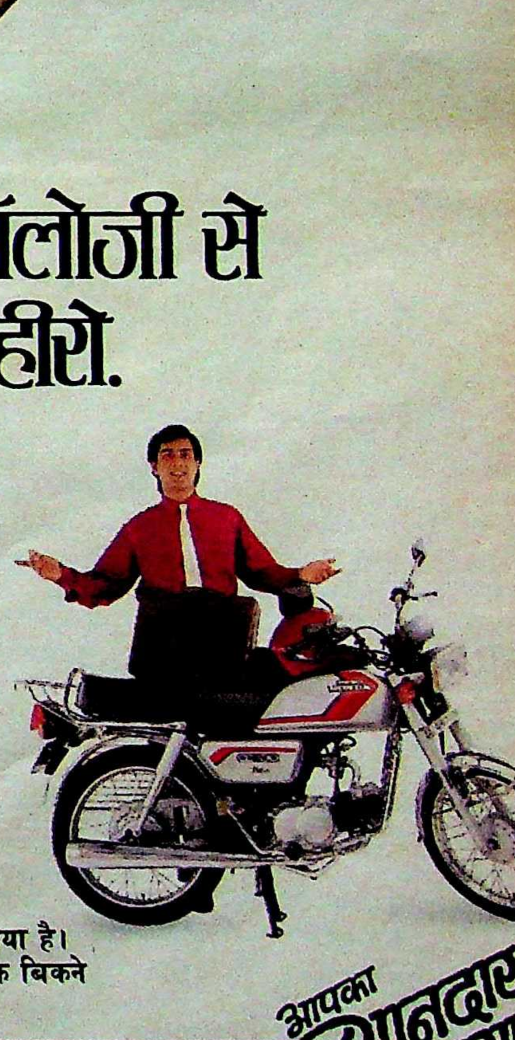

हां, हीरो होन्डा को लाखों ने अपनाया है। उन्हीं ने इसे भारत की सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिल बनाया है।

**HERO
HONDA**

आपका शानदार हमसफ़र!

* 40 कि. मी. प्रति घंटा और 130 किलो भार सहित.

HTA 6330HI

जयदेव बघेल

चौकीदार से विश्वविख्यात कलाकार

बस्तर जिले के कोंडागांव कस्बे में जन्मे जयदेव बघेल एक ऐसे विश्वविख्यात कलाकार हैं, जिन्होंने बस्तर की घड़वा जाति की दुर्लभ 'घड़वा कला' को जीवित ही नहीं रखा, विश्व स्तर पर मान दिलाया है। यह 'घड़वा कला' क्या है और इस कला को प्रतिष्ठित करने के लिए बघेल को किस प्रकार का संघर्ष और श्रम करना पड़ा है?

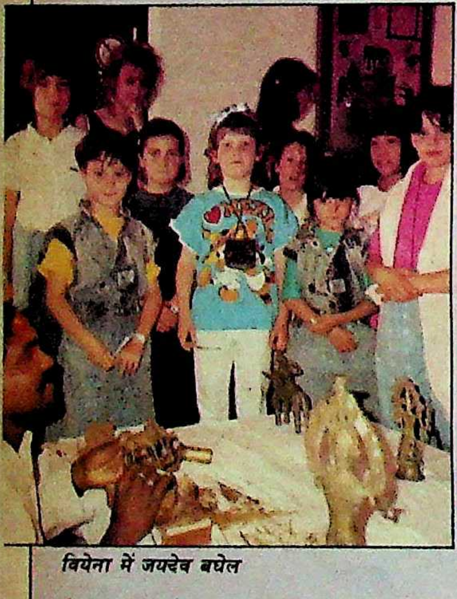

वियेना में जयदेव बघेल

'गुदड़ी में लाल' होने का मुहावरा तब सार्थक होता है जब विपन्नता के बीच से कोई महान व्यक्तित्व उभर आता है। गरीबी के अनेकानेक किस्सोंवाले बस्तर (मध्य प्रदेश) के जयदेव बघेल एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्हें पिछले १२ वर्षों के दौरान दुनियाभर के कलाप्रेमियों की सराहना व उनका सम्मान मिला है और उनके साथ बस्तर की परंपरागत लोककला 'घड़वा कला' को भी, जिसकी हाल तक घोर उपेक्षा होती रही है।

कलाकार और जोखिम : आदिवासीबहुल बस्तर जिले के कोंडागांव कस्बे में जन्मे (१९४९) जयदेव बघेल के पिता सिरमन बघेल घड़वा कला के श्रेष्ठ शिल्पी रहे हैं। जयदेव की इस कला में बचपन से ही गहरी रुचि रही है। जब सिरमन बघेल इस बहुस्तरीय कला के निर्माण में लग जाते थे, तब पास बैठा बालक जयदेव भूख-प्यास बिसार कर, मुग्ध होकर पिता के कार्य को घंटों देखा करता था। लेकिन हाय रे गरीबी! सिरमन बघेल जब परिवार के भरण-पोषण में समर्थ न हो सके, तो युवक जयदेव बघेल को दंडकारण्य परियोजना में चौकीदारी तक करनी पड़ी (१९७०)। लेकिन कला-प्रतिभा को यह 'सर्वथा अपमानजनक' नौकरी कैसे रास आती? उसे अपनी पैतृक कला की सुधियां सताने लगीं। घर की आर्थिक हालत अब भी वही पुरानी थी, फिर भी जयदेव बघेल ने जोखिम उठाया, नौकरी छोड़ दी और घर पर पिता के पास बैठकर 'घड़वा कला' की साधना नये सिरे से शुरू कर दी। ...और साधना का फल देखिये कि दो साल बाद ही जयदेव बघेल एक बड़े कलाकार के रूप में चर्चा का विषय बन गये! दरअसल जयदेव बघेल ने १९७२ में एक जोखिम और उठाया—कदम-कदम कठिनाइयों से जूझते हुए अकेले दम के परिश्रम-प्रयास से अपनी घड़वा कलाकृतियों की कलकत्ते में प्रदर्शनी लगाने का जोखिम। यह जोखिम उनके लिए वरदान साबित हुआ और अगले वर्षों में जयदेव बघेल राष्ट्र-स्तर से विश्व-स्तर के कलाकार बन गये।

निर्माण की प्रक्रिया : घड़वा कला वस्तुत: मिट्टी के जरिए कांसे को कलाकृति के रूप में ढालने का बहुत ही श्रम एवं समयसाध्य शिल्प है। यह बस्तर की घड़वा जनजाति का परंपरागत कलाकर्म है जो इस जनजाति के परिवारों के भरण-पोषण का माध्यम भी रहा है। यह कला इतनी दुष्कर और समयसाध्य है कि कभी-कभी एक कलाकृति तैयार करने में कलाकार और उसके परिवार को दो महीने लग जाते हैं। जैसे कुंभार के कार्य में परिवार के अन्य सदस्य हाथ बंटाते हैं, वैसे ही घड़वा कलाकार के कार्य में भी।

कुल नौ चरणों में पूरी होनेवाली घड़वा कला के प्रथम चरण में खेत से काली मिट्टी लाकर, उसे भिगाकर, गीली मिट्टी में धान का भूसा मिलाकर, उससे मनचाही आकृति तैयार कर ली जाती है। मिट्टी की यह आकृति धूप में सुखा ली जाती है। दूसरे चरण में नदी से 'रूई मिट्टी' लाकर उसमें गोबर मिलाकर, उसका पतला लेप मिट्टी की सूखी आकृति पर लगाया जाता है। तीसरे

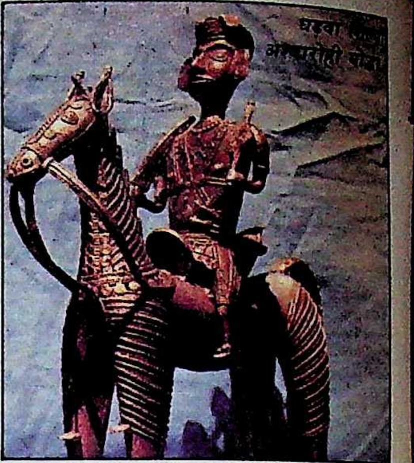

साक्षात्कार : जयदेव बघेल

जोखिम ही कलाकार को ऊपर उठाता है

माया : घड़वा कला के प्रचलित मुहावरों को तोड़कर उसमें आधुनिक कला-मुहावरों के प्रयोग का विचार यकायक आपके मन में कैसे आया?

जयदेव : *१९७२ में कलकत्ता में आयोजित अपनी पहली कला प्रदर्शनी के बाद मुझे निश्चित रूप से यह लगने लगा था कि घड़वा कला-माध्यम को गंभीरता से लेकर कुछ नया करना चाहिए। १९७६ में जब मैंने बंबई में दूसरी बार अपनी प्रदर्शनी आयोजित की, तो उस समय रघुनाथ सिन्हा ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मुझे घड़वा कला में कुछ नया करने का जोखिम उठाना चाहिए। मुझे इससे बहुत बल मिला और मैंने १९७६ के बाद घड़वा कला को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। नये-नये प्रयोग उसमें करना शुरू किया। मेरी मान्यता है कि कलाकार को जोखिम उठाने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जोखिम ही कलाकार को ऊपर उठाता है।*

माया : घड़वा कला के प्रति आपके आकर्षण का कारण क्या था? पारिवारिक पृष्ठभूमि या कुछ और?

जयदेव : *हमारा परिवार परंपरागत रूप से घड़वा परिवार था। मेरे पिता सिरमन बघेल स्वयं एक सधे हुए कलाकार थे। एक तरह से मेरे पिता ही मेरे गुरु थे। बचपन से ही मेरे भीतर घड़वा कला को लेकर एक जबरदस्त आकर्षण था। घड़वा कला के प्रति अपने*

चरण में मिट्टी की आकृति को पुनः धूप में सुखा कर उसे काट-छांट कर तराश लिया जाता है। चौथे चरण में मिट्टी की आकृति पर पुनः मिट्टी का पतला लेप लगाकर धूप में सुखा लिया जाता है।

घड़वा कला के निर्माण के पांचवें चरण में मधुमक्खी की मोम को किसी बर्तन में गर्म कर और उसमें पानी मिलाकर मोम की 'सेवई' (पतले तार जैसी) बना ली जाती है। मिट्टी की आकृति पर सेम की पत्तियों के रस का लेप कर बाद में इसी मोम के तार को एक-एक कर मिट्टी की आकृति पर लगाया जाता है।

छठे चरण में नदी की मिट्टी को पाउडर की तरह बारीक पीसकर उसमें कोयले का बारीक चूरा तथा गोबर मिलाकर आटे की तरह गूंद लिया जाता है। बाद में इसे मिट्टी की आकृति पर लगाया जाता है। मिट्टी की आकृति में कांसे की धातु को भरने के लिए ऊपर एक छिद्र भी बना लिया जाता है। मिट्टी की आकृति को पुनः धूप में सुखा लिया जाता है।

सातवें चरण में जंगल से 'डेंगूर मिट्टी' (दीमक की बांबी की मिट्टी) लाकर उसे पानी में भिगाकर उसमें भूसे का मिश्रण कर उसे आटे की तरह गूंद लिया जाता है और पुनः इसका लेप मिट्टी की आकृति पर लगांया जाता है। लेप लगाने के पश्चात पुनः इसे धूप में सुखा लिया जाता है। आठवें चरण में कांसे को पिघलाकर पूर्व में छोड़े गये छिद्र के माध्यम से मिट्टी की आकृति में भर लिया जाता है। बाद में 'डेंगूर मिट्टी' से उस छिद्र को बंद कर लिया जाता है।

घड़वा कला के निर्माण के अंतिम चरण में मिट्टी की आकृति को 'दुखना खोदरा' (आग की भट्ठी) में पकाया जाता है। दुखना खोदरा में पकने के बाद मूर्ति के बाहर की मिट्टी को तोड़कर निकाल दिया जाता है। बाहर की मिट्टी को निकाल देने के पश्चात कांसे की ठोस घड़वा मूर्ति के निर्माण का चक्र पूर्ण हो जाता है।

जयदेव का योगदान: जयदेव बघेल ने ही पहली बार घड़वा कला-माध्यम को बस्तर से बाहर ले जा कर व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया। जयदेव बघेल के पूर्व घड़वा कला केवल बस्तर के आदिवासियों तक ही सिमट कर रह गयी थी। १९७३ में भोपाल में तथा १९७४ में बंबई में जयदेव बघेल ने पुनः अपनी घड़वा कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की। इन प्रदर्शनियों से जयदेव बघेल को घड़वा कला में कुछ नया करने की प्रेरणा तो मिली, पर घर की आर्थिक स्थिति ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। घर का खर्च चलाने के लिये उस समय डेढ़ सौ रुपए में खरीदे गये अपने प्रिय ट्रांजिस्टर को उन्हें सत्तर रुपए में बेचना पड़ा। अगर १९७७ में जयदेव बघेल को उनकी घड़वा कलाकृति 'धनकुल' पर ढाई हजार रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बैंक से दो हजार रुपए का ऋण नहीं मिलता, तो वे शायद अपने कलाकर्म को सदा के लिये त्यागकर दंडकारण्य प्रोजेक्ट में अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चले जाते।

जयदेव बघेल जैसे लोक कलाकार का सबसे महत्वपूर्ण अवदान यह है कि उन्होंने घड़वा कला की परंपरा को प्रचलित रूपाकारों से बाहर निकालकर उसे मानवीय संवेदना के नये मुहावरों से परिचित करवाया है।

बस्तर के इस लोक कलाकार की अब तक एक दर्जन से अधिक कला-प्रदर्शनियां सोवियत रूस, लंदन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि विभिन्न देशों में आयोजित हो चुकी हैं। जयदेव बघेल की 'घड़वा' कलाकृतियों को पूरी दुनिया के कलाप्रेमियों ने न केवल सराहा है, बल्कि सम्मानित भी किया है।

बस्तर के बाहर जयदेव बघेल की 'घड़वा कला' को पहला सम्मान १९७७ में मिला, जब उनके बनाये 'धनकुल' पर उन्हें पहला राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। १९८२ में मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा सम्मान 'शिखर सम्मान' भी उन्हें मिला। घड़वा कला की ही बदौलत उन्हें १९८२ से १९८५ तक 'बैंक आफ इंडिया' के डायरेक्टर पद पर रहने का सम्मान मिला। इस बीच प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक सलाहकार श्रीमती पुपुल जयकर द्वारा जयदेव बघेल को राज्यसभा की सदस्यता के लिए भी पूछा गया था। आज जयदेव बघेल घड़वा कला के लोक कलाकारों में सबसे अग्रणी हैं।

—रमेश अनुपम

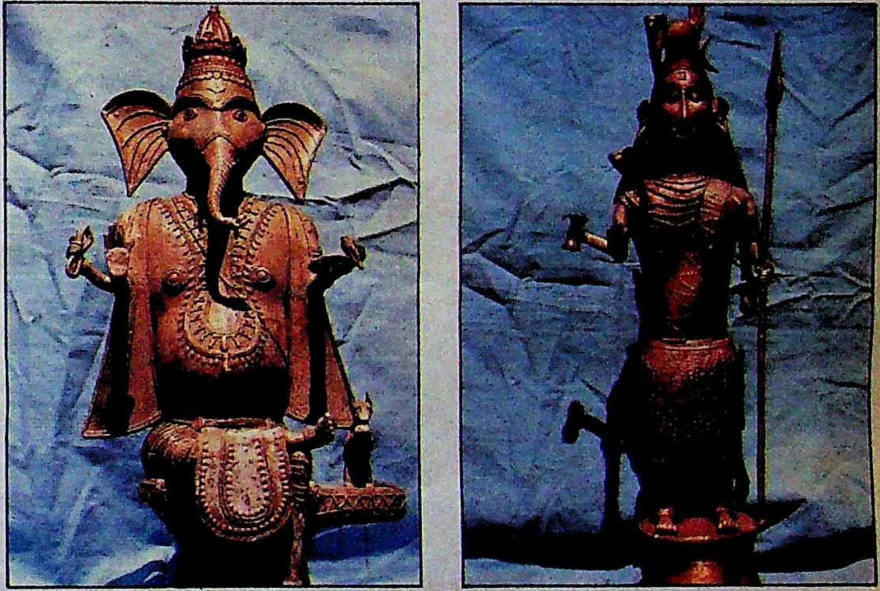

घड़वा शिल्प में गणपति (बायें) और महादेव (दायें)

आकर्षण का मूल कारण मुझे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ज्यादा लगती है।

माया: *बस्तर तक सीमित घड़वा कला को पूरे देश और विदेश से परिचित करवाने का विचार आपके मन में कैसे आया?*

जयदेव: *मैं अपने पिता की तरह घड़वा कला को केवल अपने परिवार के भरण-पोषण का माध्यम नहीं मानता था, बल्कि उसे अन्य कलाकर्मों की तरह एक विशिष्ट कलाकर्म मानता था। मुझे हमेशा यह लगता था कि बस्तर तक सीमित और काफी हद तक उपेक्षित यह कलाकर्म कोई साधारण कलाकर्म नहीं है। मैं इसे बस्तर से बाहर निकालना चाहता था। यही कारण है कि आर्थिक रूप से तंगहाली के बावजूद मैंने अपने स्वयं के प्रयासों से कलकत्ता, भोपाल और बंबई में अपनी प्रदर्शनियां आयोजित कीं। उस समय भी यह सोचकर अच्छा लगता था कि मैं घड़वा जैसे लोक कलाकर्म को बस्तर की परिधि से बाहर निकालने में कामयाब तो हुआ ही।*

माया: अब, जब आपको घड़वा कला के कारण इतना अधिक मान-सम्मान मिल रहा है, बीते दिनों को याद करके कैसा लगता है।

जयदेव: *मैं उन दिनों को भला कैसे भूल सकता हूं? मैंने अपने प्रारंभिक दिनों में बहुत कष्ट सहे हैं। बहुत गरीबी देखी है। १९८२ में मुझे जब श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों से 'शिखर सम्मान' प्राप्त करने का अवसर मिला, तब मुझे लगा कि मेरा परिश्रम सफल हुआ है।*

माया: घड़वा कला के प्रचार-प्रसार के लिये आप क्या कर रहे हैं?

जयदेव: *प्रचार-प्रसार के लिए मैंने घड़वा कला का विधिवत प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि यह कला बस्तर के बाहर भी फैले।*

—रमेश

“टाटा स्टील में ऊर्जा प्रबन्ध है जीवन का एक अंग... टिस्टेक के सारे प्रयासों का केन्द्र बिन्दु।”

श्री ए. अहमद, डिविजनल मैनेजर, एनर्जी एवं इकोनॉमी डिपार्टमेन्ट के मन में टाटा स्टील में ऊर्जा संरक्षण और उपयोग के बारे में टिस्टेक की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। इसका लम्बा इतिहास है जिसे प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है।

सन् १९२८ से यह कहानी आरंभ होती है जब विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी टाटा स्टील ने एक स्वतंत्र ऊर्जा एवं मितव्यय विभाग (एनर्जी एवं इकोनॉमी डिपार्टमेन्ट) की स्थापना की।

इसका लाभ मिला जब १९७० के दशक में सारी दुनिया ऊर्जा संकट से ग्रस्त थी, टाटा स्टील इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, ईंधन के मूल्यों में लगातार वृद्धि के बावजूद टाटा स्टील ने ऊर्जा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक बचत की।

यही बचत विशाल आधुनिकीकरण में काम आई जिससे और भी ऊर्जा की बचत करने में सहायता मिली।

आज, दुनिया में ऊर्जा का भण्डार तेजी से खत्म होता जा रहा है और ऊर्जा की कीमत आसमान छूने लगी है। इसलिये सारी दुनिया के उद्योग ऊर्जा को बचाने के लिये नई नई खोज में जुटे हैं।

आज, भारतीय कारखानों में ऊर्जा-संरक्षण की दृष्टि से टाटा स्टील सबसे आगे है। ऊर्जा संरक्षण के इस दौर में भारत का स्थान पीछे होते हुए भी टाटा स्टील सही दिशा में अग्रसर है।

एनर्जी एवं इकोनॉमी डिपार्टमेन्ट की बिल्डिंग

ENERGY
PLANNER

इस क्षेत्र में बल देने के लिये टाटा स्टील आज, जामाडोबा में वाशरी के रद्दी कोयले से बिजली का उत्पादन कर रहा है। ९९% कार्यकुशलता के साथ वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लान्ट चला रहा है। ब्लास्ट फर्नेसों में कोक के उपयोग में कटौती हो रही है। स्टील मेल्टिंग फर्नेसों में हीट-टाइम कम किया जा रहा है। सोकिंग पिट और रीहीटिंग फर्नेसों में एल डी शॉप का टॉप गैस उपयोग में लाया जा रहा है। स्टैम्प चार्जिंग तकनीक के प्रयोग से लो-ग्रेड कोयले से हाई-ग्रेड कोक बनाया जा रहा है। अब सिन्टर बनता है ब्लू डस्ट से, जो पहले खानों में बेकार पड़ा रहता था।

TISTECH
ENERGY

टिस्टेक ऊर्जा, स्टील प्लान्टों के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक मार्गदर्शक प्रयास—जिसका लक्ष्य है एक प्रासंगिक तकनीक का उद्भावन, एक आधुनिक प्रगतिशील-धारणा का प्रसारण। आने वाले कल के प्रयोजन को न भूल कर आज के जमाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के वायदों का एक और नाम है—टिस्टेक!

- **निर्धारित ऊर्जा की खपत में प्रति वर्ष १.४ प्रतिशत की कमी।**
- **सिन्टर बनाने के लिये ब्लू डस्ट फाइन्स ५० प्रतिशत वसूली।**
- **वाशरी के रद्दी कोयले के उपयोग से बिजली का उत्पादन।**
- **एल डी टॉप गैस का उपयोग करके ८००० के एल ईंधन ऑयल की बचत।**
- **स्टील मेल्टिंग शॉप में उत्पादन को दुगना करने के लिये कॉर्फ तकनीक का प्रयोग।**
- **कॉन्कास्ट के उपयोग से प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की खपत को समाप्त कर दिया गया है।**

टाटा स्टील
सबसे पहले सबसे आगे

नये सिन्टर प्लान्ट का कंट्रोल रूम

E7000
TATA STEEL
ENERGY SAVING CAMPAIGN
First into the
New Sinter Plant Inaugurat

रीता भादुड़ी, रूपा गांगुली, पल्लवी जोशी

छोटे परदे पर जिनका वर्चस्व है !

पिछले दिनों एक प्रख्यात एजेंसी 'एक्सप्रेशंस इंडिया' ने सभी वर्ग के दूरदर्शन दर्शकों का सर्वेक्षण कराया, तो अभिनय तथा लोकप्रियता की दृष्टि से जो १० अभिनेत्रियां चुनी गयीं, उनमें अव्वल नंबर रहा रीता भादुड़ी ('मुजरिम हाजिर') का। दूसरे पर रहीं रूपा गांगुली ('महाभारत') और तीसरे पर पल्लवी जोशी ('भारत : एक खोज')। अभिनय, संवाद-अदायगी, भावसंप्रेषण तथा लोकप्रियता में शत-प्रतिशत अंक सिर्फ रीता भादुड़ी को मिले। हर एक का मानना था कि इतना सशक्त अभिनय करने के बाद भी रीता भादुड़ी में क्या कमी है कि वे स्टार-अभिनेत्री नहीं बन सकीं ? जबकि द्रौपदी की भूमिका में रूपा गांगुली के बारे में दर्शकों का कहना था कि अगर वे 'महाभारत' में बहुचर्चित द्रौपदी की भूमिका के बजाय दूसरी कोई भूमिका कर रही होतीं, तो वे सामान्य अभिनेत्री भर बन कर रह गयी होतीं। पल्लवी जोशी के बारे में दर्शकों का मानना था कि वे बहुत अच्छी अभिनेत्री बन सकती हैं, बशर्ते अपनी भूमिकाओं और निर्देशकों के चुनाव पर ध्यान दें।

रीता भादुड़ी : रीता भादुड़ी एक सशक्त अभिनेत्री होने के बावजूद सफल स्टार-अभिनेत्री क्यों नहीं बन सकीं, दर्शकों का यह सवाल जायज था, क्योंकि उन्होंने फिल्म या टीवी सीरियलों में काम करते समय तकरीबन अपनी हर भूमिका में प्रभाव छोड़ा था। "नहीं, मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं रहा कि मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वह स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था।" रीता भादुड़ी 'माया' को बतलाती हैं, "फिल्म इंस्टीट्यूट से आनेवाला हर कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा या शबाना आजमी जैसा स्थान नहीं बना पाता, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसमें प्रतिभा ही नहीं है। यह सारा दोष तो आज फिल्म मेकिंग और फिल्म निर्माताओं की सोच का है, जो कभी भी नाक के नीचे देखने की कोशिश नहीं करते। हिंदी फिल्मवालों ने मुझे वह रुतबा नहीं दिया, तो मेरा क्या बिगड़ गया, मलयालम और गुजराती फिल्मों तथा दूरदर्शन ने तो दिया। मैं कभी बेकार तो नहीं रही न, मुझे (दूसरों की तरह) फिल्मों में रोल पाने के लिए गलत समझौते तो नहीं करने पड़े और दर-दर भटकना तो नहीं पड़ा न ! ढेर सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, गाड़ी-बंगलों तथा नौकरों की फौज की चाह मुझे कभी नहीं रही।"

रीता भादुड़ी

१९७३ में फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में रीता के बैच में शबाना आजमी, जरीना वहाब, कंवलजीत, मोहन (मलयालम फिल्मों का सुपर स्टार), प्रीति गांगुली (अशोक कुमार की बेटी) आदि कुल २२ छात्र-छात्राएं थीं। यह इंस्टीट्यूट के इतिहास में अभिनय के छात्रों का सबसे बड़ा बैच था। फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलते ही १९७३ में रीता को मलयालम फिल्म 'कन्याकुमारी' में नायिका की भूमिका मिली, नायक थे— कमल हासन। इसके पहले उन्होंने 'आईना' में मुमताज की बहन की महत्वपूर्ण भूमिका की थी, जिसमें कमल हासन जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से काम कर रहे थे। फिर रीता ने सेथु माधवन की मलयालम फिल्म 'चट्टाकरी' में नायिका की भूमिका की, लेकिन वायदे के बावजूद 'चट्टाकरी' का हिंदी-रीमेक 'जूली' बनाते समय नायिका की भूमिका रीता को देने के बजाय लक्ष्मी को दे दी और उन्हें नायक की बहन की भूमिका थमा दी। रीता का कहना है, "सेथु माधवन की मैं इज्जत करती थी, तब उनकी बात टालने की, मुझ नयी अभिनेत्री में हिम्मत भी नहीं थी। फिर बहन की भूमिका निभा चुकी थी।"

'आईना' बाक्स आफिस पर अच्छी फिल्म होने तथा रीता और मुमताज के सशक्त अभिनय के बावजूद फ्लाप हो गयी थी, लेकिन 'जूली' की बाक्स आफिस सफलता तथा रीता के बेजोड़ अभिनय ने उनके इर्द-गिर्द फिल्म निर्माताओं की लाइन लगा दी, लेकिन उनका दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि निर्माता रीता को सिर्फ बहन की भूमिका देना चाहते थे।

ठीक ऐसे ही समय, जब रीता अपने 'टाइप्ड इमेज' से जूझ रही थीं, १९७५ में उन्हें गुजराती फिल्म 'लाखन फुलानी' में नायिका की भूमिका मिल गयी और रीता ने यह सोच कर कि कुछ नहीं तो यही सही फिल्म स्वीकार कर ली। फिल्म बाक्स आफिस पर कुछ इस तरह हिट हुई कि गुजराती फिल्मों के मार्केट में उनकी मांग चरम सीमा पर पहुंच गयी। एक दशक की अवधि में उन्होंने ७४ गुजराती फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाकर एक कीर्तिमान कायम किया। इनमें से अधिकतर फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं, कुछ औसत थीं, लेकिन एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो बाक्स आफिस पर पिटी हो।

राकेश चौधरी ने 'बनते-बिगड़ते' सीरियल में रीता को काम तो दिया ही 'चुनौती' में उन्हें अतिथि भूमिका भी दी और उसके बाद 'मुजरिम हाजिर' में नायिका की भूमिका दी। इसी तरह जब वे 'बनते-बिगड़ते' में काम कर रही थीं, तो निर्माता-निर्देशक क्षीरसागर ने उन्हें 'खानदान' सीरियल में एक छोटी, किंतु अहम भूमिका दी फिर 'स्त्री' सीरियल के अधिकांश एपीसोडों में नायिका की भूमिका दी। 'स्त्री' में रीता ने विवादास्पद पुलिस उपायुक्त किरण बेदी की भूमिका निभायी थी।

रीता के कैरियर में असली भूमिका निभायी 'दूरदर्शन' ने। महानगरों से लेकर सुदूर गांवों में बैठे करोड़ों दर्शकों से रूबरू कराया। इसके बाद पहचान का दायरा बढ़ता चला गया। 'मुजरिम हाजिर' में रीता के कैरियर की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसमें एक स्त्री के भिन्न-भिन्न रूपों को बखूबी पेश किया गया है। 'मुजरिम हाजिर' में रीता के प्रभावशाली अभिनय से प्रभावित हो फिल्म निर्माता पुनः उनके घर का चक्कर काटने लगे हैं।

रूपा गांगुली : टीवी पर 'महाभारत' का द्रौपदी चीर-हरण का दृश्य चल रहा था। हर कोई अपना काम पूरा या अधूरा छोड़कर सेट से चिपक कर बैठ गया था। चीर-हरण का दृश्य पूरा हुआ, तो एक दर्शक बड़े हतोत्साहित स्वर में बोला, "द्रौपदी का इससे अधिक अंग तो हम 'गणदेवता' में देख चुके थे, फिर चीर-हरण का फायदा क्या हुआ ?" यह प्रतिक्रिया सिर्फ उस एक दर्शक की नहीं थी, भारत के भिन्न-भिन्न कोनों में रहनेवाले लाखों शहरी-गंवई दर्शकों की थी।

रूपा गांगुली जब द्रौपदी के कास्ट्यूम में पहली बार दर्शकों के सामने आयीं, तो उन्होंने उसके भीतर उस दुर्गा को तलाशने की कोशिश की जिसे वे अपेक्षाकृत कम पोशाक में 'गणदेवता' में देख चुके थे। राजसी वेशभूषा में अलंकृत रूपा तब

उन्हें किशोरी द्रौपदी से उम्र में काफी बड़ी भी लगी थी। द्रौपदी के रूप में रूपा के चुनाव की तब आलोचना भी कम नहीं हुई थी।

समुद्र, एकांत, संगीत और किताबों की बेहद शौकीन रूपा की अभिनय-यात्रा १९८६ में उनके रिश्ते के नाना बिजाय चटर्जी के बंगला सीरियल 'मुक्तबंदो' के एपीसोडों 'स्त्री का पत्र' तथा 'निरुपमा' से शुरू हुई थी। यों वे आर्किटेक्ट बनना चाहती थीं और उस समय बीए (अंतिम वर्ष) की छात्रा थीं। इसके बाद उनकी इच्छा आईएएस में बैठने की थी। 'मुक्तबंदो' में उन्होंने यह सोच कर काम किया था कि उनके कैरियर का यहीं अंत हो जायेगा। रूपा बतलाती हैं, "लेकिन फिल्म-एक्टिंग एक तरह का धीमा-जहर है, जो शरीर में फैलते-फैलते उसे पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लेता है। फिर तो एक के बाद दूसरे सीरियलों ('ओबिनंद भोगिख्य', 'दलका रासी', 'चोखे जोर', 'राग क़नोराग', 'ओगनी ओ सहा' तथा फिल्मों ('पहली प्रतीक', 'राग-अनुराग', 'अलका हंसी', 'एक दिन अचानक') में काम मिलता चला गया। अब तो अभिनय ही मेरी जिंदगी बन गयी है। मैं एक सशक्त अभिनेत्री बनना चाहती हूं।"

रूपा अंग-प्रदर्शन, स्वीमिंग सूट या टू-पीस पहनने तथा बेडरूम दृश्य देने के बरखिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने विनोद पांडे की 'सच' तथा दूसरी कई फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। लेकिन इत्तिफाक यह कि उनकी महत्वपूर्ण अभिनय शुरुआत 'गणदेवता' से हुई, जिसमें उन्हें बिना ब्लाउज की साड़ी पहननी थी।

रूपा स्टारडम की सीमा-रेखा के निकट पहुंच रही हैं। 'अमन के फरिश्ते' में जावेद जाफरी के साथ डिस्को-ब्रेकडांस कर इन्होंने इसका प्रमाण दे दिया है। तेजी से बंबइया कामर्शियल फिल्में साइन करना भी शुरू कर दिया है—फिल्मी सितारों पर लगी पाबंदी का फायदा भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन द्रौपदी के अभिनय को वे अभिनय का एक लंबा पड़ाव मानती हैं जिसमें उन्हें अभिनय के विभिन्न आयामों का मौका मिला है। यों रूपा इस समय बंगला फिल्मों के साथ-साथ बंगला सीरियल 'गल्पो आर गल्पो' में भी काम कर रही हैं।

पल्लवी जोशी : श्याम बेनेगल ने 'भारत : एक खोज' में ओमपुरी एवं अंजन श्रीवास्तव के अलावा जिस अभिनेत्री को अधिकतर एपीसोडों में विभिन्न भूमिकाओं में दुहराया, वह हैं—पल्लवी जोशी, जिन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म 'सुसमन' में शबाना आजमी, ओमपुरी के समानांतर भूमिका बड़े प्रभावशाली ढंग से निभायी थी। हालीवुड में बननेवाली फिल्म 'टू वर्जिस' में एक नायिका की भूमिका निभाकर तथा नबेंदु घोष की 'तृषाग्नि' में बोल्ड दृश्य देकर पल्लवी चर्चाओं का केंद्र बनी हुई हैं। आज टेलीकास्ट होनेवाले हर तीसरे-चौथे सीरियल या उसके किसी-न-किसी एपीसोड में पल्लवी अपने अभिनय का प्रभाव जरूर छोड़ जाती हैं। 'एक कहानी', 'कथासागर', 'लेनादेना', 'खरी-खरी', 'खजाना', 'रिश्ते-नाते', 'चेहरे', 'अदालत', 'बुनियाद', 'कालाजल', 'हम हिंदुस्तानी', 'किस्से मियां-बीवी के', 'और भी हैं राहें', 'मि० योगी', 'कब तक पुकारूं' आदि दर्जनों सीरियलों में वे काम कर चुकी हैं और लगभग इतने ही सीरियलों में काम कर रही या अनुबंधित हैं। इस समय वे टीवी स्टारडम के शिखर पर पहुंची हुई हैं। इसके साथ-साथ फिल्मों में भी काम कर रही हैं।

पल्लवी ने तीन वर्ष की उम्र में 'नाग मेरे साथी' में सुजीत कुमार तथा गुजराती फिल्म 'खम्मा मारा वीरा' में सारिका के बचपन की भूमिका निभायी थी जिसके लिए गुजरात स्टेट बेस्ट चाइल्ड का उन्हें पुरस्कार भी मिला था। इस प्रकार उन्होंने १५-१६ फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं कीं। बड़ी होने पर उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ ब्यूटीशियन का कोर्स किया, मराठी-हिंदी नाटकों में अभिनय किया और रूपा गांगुली की ही तरह आर्किटेक्ट बनने का निश्चय किया।

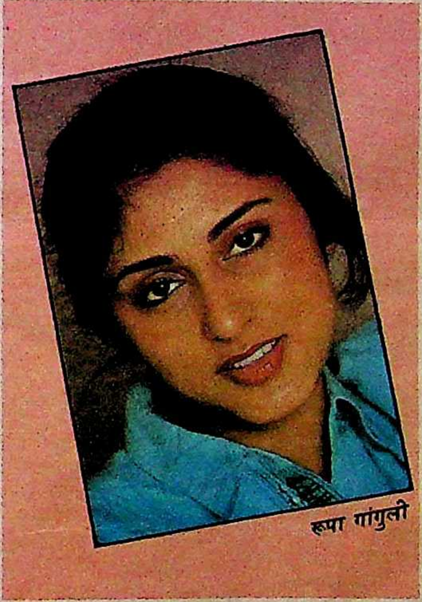
रूपा गांगुली

"मैंने कभी भी अभिनय को अपना कैरियर बनाने के बारे में शिद्दत से नहीं सोचा था। हालांकि तब भी मैं कई फिल्मों में काम कर रही थी", पल्लवी ने 'माया' को बतलाया, "दरअसल बड़ी होकर मैंने जब फिल्मों में अभिनय शुरू किया, तो मेरी उम्र इतनी कम थी कि लोग मुझे हीरोइन की भूमिका देते समय हिचकिचाते थे। उनको लगता था कि मैं हीरो के सामने उसकी प्रेमिका कम, छोटी बहन ज्यादा लगूंगी, अपनी उम्र (किशोरावस्था) के कारण। जबकि मेरा मानना था कि कैमरे के सामने कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। और फिल्म इंडस्ट्री के रवैये से जब मैं वाकिफ हुई, तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और आर्किटेक्ट बनने के बारे में सोचना छोड दिया।

पल्लवी ने स्व० जुगल किशोर की फिल्म 'दादा' में अंधी लड़की की भूमिका निभायी थी। मंजु सिंह को उनका अभिनय याद था, इसलिए उन्होंने अपने टीवी सीरियल 'एक कहानी' के 'जंगली बूटी' नामक एपीसोड में पल्लवी को मुख्य भूमिका सौंपी। इस एपीसोड का निर्देशन दयाल निहलानी (श्याम बेनेगल के तत्कालीन सहायक तथा गोविंद निहलानी के भाई) ने किया था। उन्होंने श्याम बेनेगल को जब 'जंगली बूटी' का कैसेट दिखलाया, तो वे पल्लवी के अभिनय से काफी प्रभावित हुए और उन्हें 'सुसमन' में एक प्रमुख भूमिका दी। यहीं से वे श्याम बेनेगल के संपर्क में आयीं। दयाल निहलानी ने जब 'अंधायुद्ध' का निर्देशन किया, तो मुख्य भूमिका के लिए पल्लवी जोशी को चुना। आतंकवादी राज बब्बर की गिरफ्त में कैद, दोनों पैरों से बेकार लड़की की विवशता को पल्लवी ने बड़ी स्वाभाविकता से उजागर किया था।

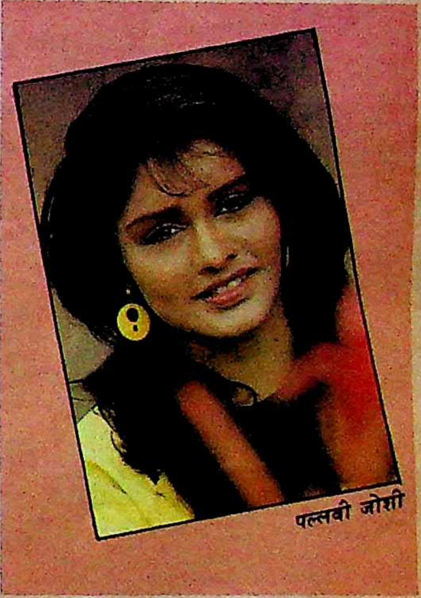
पल्लवी जोशी

पिछले चार वर्षों में पल्लवी २० से अधिक टीवी सीरियलों तथा लगभग इतनी ही फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। २० वर्ष की एक अभिनेत्री के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे वे सिर्फ मेहनत की संज्ञा देती हैं। सीरियलों के अलावा उन्होंने 'क्रोध' में सनी देवल तथा 'इंसानियत' में अमिताभ बच्चन के साथ पागल लड़की की भूमिका भी की थी। अमिताभ की सलाह पर उन्होंने वहीदा रहमान की पागल भूमिका वाली फिल्म 'खामोशी' को दर्जनों बार देखा। 'वंचित' में अपने बोल्ड पोज तथा 'तृषाग्नि' में एक्सपोजर एवं उत्तेजक चुंबन दृश्यों के लिए वे काफी चर्चित हो चुकी हैं।

—रवींद्र श्रीवास्तव

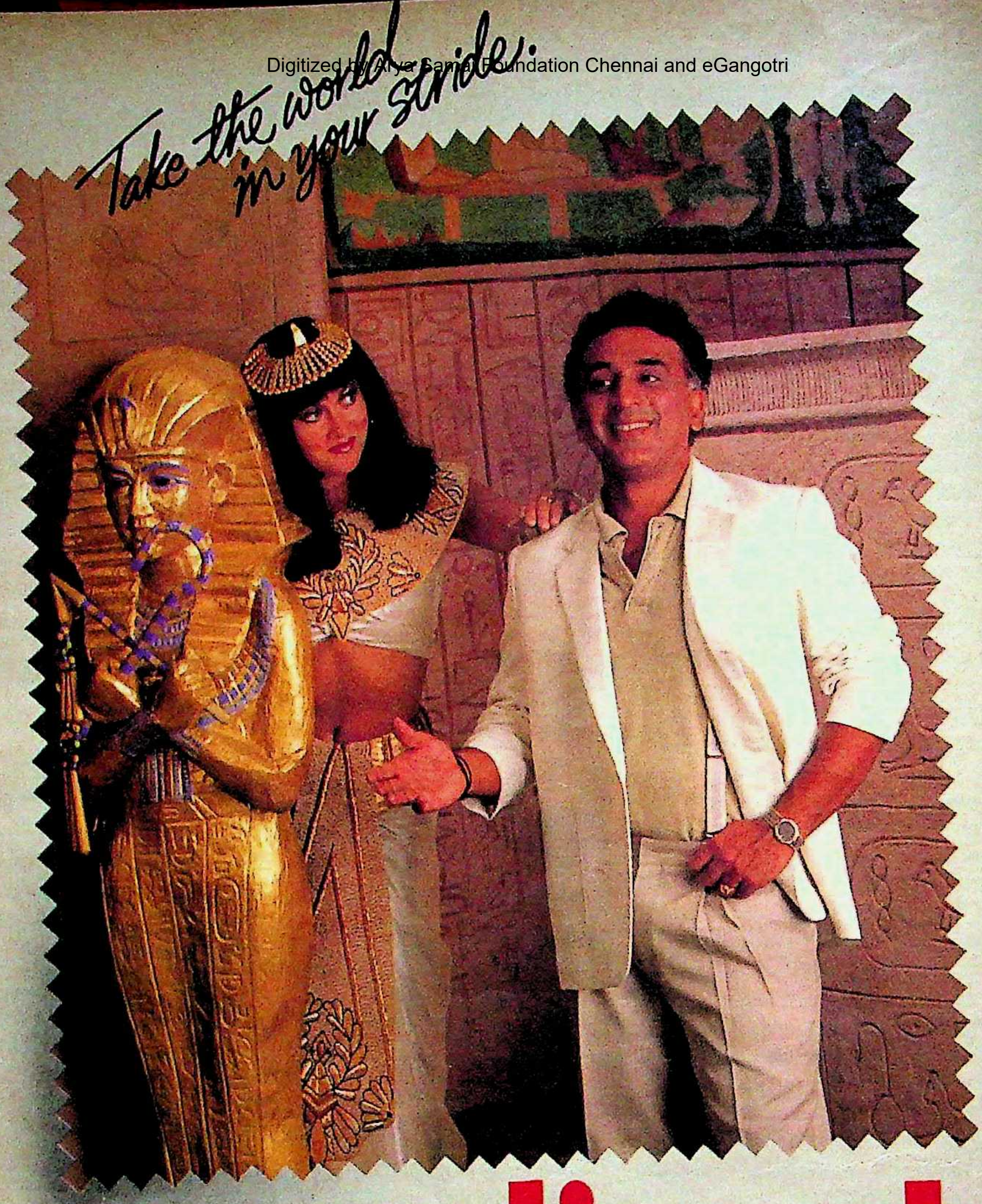
Take the world in your stride.

dinesh

Exclusives ▲ Suitings ▲ Co-ordinates ▲ Safaris

The choice of leading fashion houses, internationally.

Woolmark
HI-COMFORT
WOOL
PURE NEW WOOL

Authorised dealers: **CHANDIGARH:** Gulati Stores • T. R. & Sons • **JALANDHAR:** Fancy Textiles • M. Janki Das & Sons • **SIMLA:** Amritsar Cloth House • Rajpal Bros. • **SONEPAT:** Anil Stores • **SRINAGAR:** Bombay Selection House • Bombay Store • [illegible] • Khyber Stores • Meqbool Shah Gulam Hassan • *Tata Fabrics*

(M/6)

विपक्षी तालमेल

वाम-भाजपा की जंग

बोफोर्स, ठक्कर आयोग और सीएजी की रिपोर्ट के मामले में विपक्ष वाम-दक्षिण का भेद भुलाकर एकजुट हुआ था और ९ अगस्त के 'देश बचाओ' और ३० अगस्त के 'भारत बंद' में भी उसने अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय दिया है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा और वामपंथी दलों के नेता एक दूसरे की ऐसी आलोचना क्यों कर रहे हैं जो विपक्षी एकता के लिए घातक साबित हो सकती है?

- **बोफोर्स मुद्दे पर लगभग दो वर्ष तक संसद में साझा विपक्षी कार्रवाई।**
- **ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर संसद से साझा विपक्षी निष्कासन।**
- **सीएजी के मुद्दे पर विपक्ष का सामूहिक निर्णय और इस्तीफा।**
- **९ अगस्त को पहले देश बचाओ और फिर ३० अगस्त के भारत बंद को कामयाब बनाने में अभूतपूर्व विपक्षी एकजुटता।**

एक के बाद एक, विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष जिस एकजुटता का परिचय दे रहा था उससे यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस को हराने के लिए विपक्ष को एकजुटता का ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो गया है। किंतु जब वयोवृद्ध वामपंथी नेता ईएमएस नंबूदिरीपाद ने हाल की पोलित ब्यूरो मीटिंग की समाप्ति पर भाजपा और संप्रदायवाद को मुद्दा बनाते हुए यह घोषणा की कि 'आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध एक साझा उम्मीदवार खड़ा किये जाने की कोई संभावना नहीं है', तो विपक्षी एकजुटता एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गयी। संदेह का कारण सिर्फ नंबूदिरीपाद का ही बयान नहीं। सचाई तो यह है कि विपक्षी एकजुटता को घात लगानेवाली बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन में भाजपा भी पीछे नहीं। स्थिति यह है कि भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यदि डंके की चोट पर महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन पर डटे हैं और मार्क्सवादियों की देशभक्ति पर शक का ऐलान करते रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी वामपंथियों के ऐन गढ़ कलकत्ते में अपने पार्टीजनों को मार्क्सवादियों के खिलाफ अधिकाधिक उम्मीदवार खड़े करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। विपरीत ध्रुवों पर खड़े इन दोनों खेमों से सहयोग और चुनावी तालमेल के आकांक्षी राष्ट्रीय मोर्चे, विशेषकर जनता दल, की इस मुद्दे पर किंकर्तव्यविमूढ़ता और असमंजस आश्चर्यजनक नहीं। न ही 'अनिर्णय' का भार ढोते राष्ट्रीय मोर्चे के संयोजक और जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह का अधैर्य और आक्रोश अस्वाभाविक है जो गत दिनों की एक प्रेस कांफ्रेंस में अचानक 'दोष अनिर्णय का नहीं जटिल समस्याओं और परिस्थितियों का है जिसका समाधान न सहज है, न सरल और न ही सीधा', के उनके जवाब में फूट पड़ा। समस्या कितनी जटिल है, यह इसी से स्पष्ट है कि कल तक भाजपा की तालमेल के समर्थक कहे जानेवाले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भी हाल में भाजपा की कटु आलोचना करते हुए आक्रामक तेवर अपना लिये हैं।

ईएमएस नंबूदिरीपाद

राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सांप्रदायिकता का विषवमन करनेवाली भाजपा आज देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और धर्म निरपेक्ष चरित्र के लिए एक जबर्दस्त खतरा बन गयी है। अपने अल्पसंख्यक विरोधी रवैये के कारण एक बड़े मतदाता वर्ग को सशंकित कर वह विपक्ष को गहरा आघात पहुंचा रही है।

रस्साकशी : यह विडंबना ही है कि जितनी अनिवार्यता और विवशता आज चुनावी एकजुटता की है, उतनी ही कशमकश और रस्साकशी विभिन्न विपक्षी दलों के भीतर-बाहर व्याप्त है। एकजुट करने के लिए यदि सामने दिखायी देती सत्ता है, तो बिगाड़ पैदा करने के लिए उसी तीव्रता से अपना वर्चस्व स्थापित करने की आकांक्षा भी। लामबंद करने के लिए एक ओर यदि जनमत का भरपूर दबाव है, तो दूसरी ओर अंतर्विरोधी विचारधाराओं का अलगाव है। यद्यपि यह अहसास सर्वव्यापी है कि सामूहिक प्रयास ही राजीव सरकार हटाने के उद्देश्य की प्राप्ति करायेगा, फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर शीर्ष नेतृत्व में अहं का टकराव है और अपनी-अपनी गोटी लाल करने की लालसा।

सौ वर्ष से अधिक पुरानी, भीमकाय कांग्रेस को पछाड़ने के लिए चुनाव में उसके विरुद्ध एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना एक ऐसी ऐतिहासिक आवश्यकता है, जिससे कोई भी विपक्षी दल अनभिज्ञ नहीं। १९७७ के चुनाव परिणामों के अपवाद के अतिरिक्त कांग्रेस सदा ही विपक्षी वोटों के बिखराव का लाभ उठाकर ५० प्रतिशत से भी कम वोटों से लगातार गद्दीनशीं होती रही है। यहां तक कि १९८४ की आंधी के बावजूद राजीव गांधी मात्र ४८ प्रतिशत वोट ही बटोर पाये थे। ऐसे में कमरतोड़ मंहगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार से त्रस्त मतदाताओं के व्यापक आक्रोश को भुनाने के लिए विपक्ष के विभिन्न दलों में चुनावी तालमेल की उपलब्धि ही उनकी जीत की पहली शर्त बन गयी है।

गौरतलब है कि विपक्षी एकजुटता के प्रथम दो चरणों—विलय जो चार दलों लोकदल-ब, संजय विचार मंच, जनमोर्चा और जनता पार्टी के एकजुट हो जनता दल के रूप में और क्षेत्रीय पार्टियों—तेलुगुदेशम, द्रमुक, अगप और

लालकृष्ण आडवाणी

मार्क्सवादी ऐंठ-अहं का मुख्य कारण मात्र यही है कि उनकी दो राज्यों में सरकारें हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि देश की ५४३ लोकसभा सीटों में ४२५ ऐसी हैं, जहां मार्क्सवादियों का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां वे क्या करते हैं या क्या नहीं करते इसका चुनाव-परिणामों पर कोई असर नहीं होगा।

समाजवादी कांग्रेस के चुनावी समझौते से पूरा हुआ है। तीसरा और अंतिम चरण सीटों के तालमेल को लेकर है, जिसकी गाड़ी प्रयासों के बावजूद अभी तक स्टेशन पर अटकी पड़ी है। मूल समस्या विपरीत ध्रुवों पर बैठी वामपंथी पार्टियों और भाजपा को लेकर है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से इनका तालमेल राष्ट्रीय मोर्चे से होना है, किंतु व्यावहारिक रूप में देखा जाये, तो तालमेल निर्णायक हिंदी भाषी सात प्रदेशों में सीधे-सीधे जनता दल वामपंथ और भाजपा के मध्य होना है। अन्य प्रदेशों में किसी-न-किसी एक विपक्षी दल का वर्चस्व कायम होने के कारण तालमेल में उतनी दिक्कत नहीं है।

हमारा संघर्ष क्षेत्र अलग है: वाजपेयी

दिलचस्प तथ्य यह है कि भाजपा और वामपंथी पार्टियां न सिर्फ विचारधारा प्रधान हैं बल्कि दोनों ही अनुशासित कार्यकर्ताओं की टोली से भी लैस हैं। दोनों के सीमित, किंतु सुनिश्चित प्रभावक्षेत्र हैं। यद्यपि भाजपा का लक्ष्य है कि संसद में उसके प्रतिनिधियों की संख्या वर्तमान 'दो' से इतनी बढ़ जाये कि वह वहां धुरी बन सके, किंतु सीटों के तालमेल के वर्तमान प्रश्न पर उसने अपेक्षाकृत अधिक लचीला रवैया अपनाया है। अड़ियल और आक्रामक रुख वामपंथियों विशेषकर मार्क्सवादियों ने अपनाया है। यही तालमेल के मार्ग में फिलहाल बाधक है।

वैसे इस संबंध में जब 'माया' ने भाकपा सचिव एम फारूकी से बात की, तो वे बोले, "भाजपा के इस नये रुख का मूल कारण उसकी अवसरवादिता है। उसे भलीभांति ज्ञात है कि अपने बलबूते वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं कर सकेगी। इसीलिए अपने तथाकथित मजबूत गढ़ों—मप्र, राजस्थान, बिहार, उप्र और हिमाचल आदि में भी पूर्णतया आश्वस्त न होने के कारण वह जनता दल से हर हाल तालमेल को लालायित है। महाराष्ट्र में तो उसने संकीर्ण और फासिस्टी विचारोंवाली शिवसेना से तालमेल कर लिया है।" यही नहीं, संप्रदायवाद के विरुद्ध एक सूत्री अभियान चलानेवाले माकपा महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद ने जोड़ा, "राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सांप्रदायिकता का विषवमन करनेवाली भाजपा आज देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए एक जबर्दस्त खतरा बन गयी है। अपने अल्पसंख्यक विरोधी रवैये के कारण एक बड़े मतदाता वर्ग को सशंकित कर वह विपक्ष को गहरा आघात पहुंचा रही है।"

भाजपा का रुख: भाजपा ऐसे तीव्र कटाक्ष को चुपचाप सहनेवाली नहीं। जवाब में महासचिव किशनलाल शर्मा बोले, "मार्क्सवादी नेता पहले यह तय करें कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, राजीव गांधी अथवा संप्रदायवाद? संप्रदायवाद का जबरन और बार-बार मुद्दा उठाकर क्या वे विपक्ष में भितरघात कर कांग्रेस की सहायता नहीं कर रहे हैं?" इसमें अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने जोड़ा, "मार्क्सवादी ऐंठ-अहं का मुख्य कारण मात्र यही है कि उनकी दो राज्यों में सरकारें हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि देश की ५४३ लोकसभा सीटों में ४२५ सीटें ऐसी हैं, जहां मार्क्सवादियों का कोई प्रभाव नहीं। ऐसी स्थिति में वहां वे क्या करते हैं या क्या नहीं करते, इसका चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं होगा।"

वामपंथियों और भाजपा की आपसी तीरंदाजी का पहला शिकार बना है, जनता दल और उसके अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसीलिए विपक्षी रथ को विपरीत दिशाओं में घसीटते इन दो दलों के बीच सारथि की भूमिका निभाते और संतुलन के दुष्कर प्रयास में रत विश्वनाथ प्रताप सिंह कभी वामपंथियों को अपना स्वाभाविक सहयोगी करार देते हैं, तो कभी भाजपा के साथ एक मंच पर भाषण देते दिखायी देते हैं। इसी के चलते उन पर लग जाता है अनिर्णय, अनिश्चय का चिरपरिचित ठप्पा। इस विषम स्थिति में जनता दल की अपनी भी विवशताएं हैं। सर्वप्रथम, हरहाल चुनावी तालमेल बनाने की विवशता के बावजूद एक निश्चित संख्या से अधिक सीटें देने की स्थिति में वह नहीं है। अधिकाधिक सीटों पर लड़ने के अतिरिक्त उसकी यह भी विवशता है कि वह बहुतेरी सीटें अन्य पार्टियों को नहीं दे सकता, जहां विपक्षी जीत सुनिश्चित है। कारण विपक्ष के गद्दीनशीं होने और उस स्थिति में सबसे बड़े घटक के रूप में उभरने की पहली शर्त यही होगी कि हिंदीभाषी राज्यों की लगभग २२४ सीटों में से करीब १५० सीटों पर वह जीते। ऐसा न होने पर सारा चुनावी गणित ही गड़बड़ा जायेगा। नतीजतन विपक्ष के सत्तारूढ़ होने का अवसर तो खटाई में पड़ेगा ही, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा गुटबंदी और चुनौती का खतरा भी कम नहीं रहेगा।

कदाचित, इसीलिए तालमेल का सर्वाधिक लाभ जनता दल के खाते में जायेगा, ऐसा अनेक पर्यवेक्षकों सहित स्वयं लालकृष्ण आडवाणी का मानना है। 'माया' को उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से गत दिनों की अपनी एक भोज वार्ता सुनाते हुए बताया, "मैंने श्री सिंह से कहा कि जब मैं तालमेल संबंधी आपके अनिश्चय और ढुलमुलपन को देखता हूं, तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तालमेल में सबसे अधिक रुचि आपको होनी चाहिए। कारण, इसका सर्वाधिक लाभ जनता दल

साक्षात्कार: अटल बिहारी वाजपेयी

हम श्रीराम का नाम लेकर वोट नहीं मांगेंगे

माया: *जनता दल से भाजपा और वामपंथ दोनों के तालमेल के लिए क्या रामजन्मभूमि विवाद पर भाजपा ने कोई फैसला लिया है?*

अटल बिहारी वाजपेयी: *यह कहना गलत है कि तालमेल में रामजन्मभूमि विवाद के कारण कोई कठिनाई पैदा हो रही है। हालांकि अनेक मुद्दों पर भाजपा का दृष्टिकोण राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य दलों से भिन्न है। जैसे अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण, जैसे संविधान की धारा ३७० की समाप्ति आदि। किंतु न हम जनता दल से कह रहे हैं कि वह अपना रवैया बदले और न जनता दल हम से कह रहा है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें।*

माया: *विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए भी आप तालमेल की संभावना देखते हैं?*

वाजपेयी: *मतभेद होते हुए भी हम अपने परम लक्ष्य राजीव गांधी को हटाने को आंखों से ओझल नहीं कर सकते। जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, उनका हमारा संघर्ष क्षेत्र बिलकुल अलग है। जहां भाजपा शक्तिशाली है, उनकी संख्या नगण्य है। उनके प्रभाव क्षेत्र में हमारा विशेष प्रभाव नहीं।*

माया: *क्या रामजन्मभूमि विवाद चुनावी मुद्दा बनेगा, जैसाकि वामपंथियों को आशंका है?*

वाजपेयी: *रामजन्मभूमि का आदोलन जो लोग चला रहे हैं, उनकी दृष्टि न तो सत्ता पर है और न सीटों पर। उनके लिए रामजन्मभूमि का प्रश्न एक श्रद्धा का प्रश्न है। चुनाव का मुद्दा बनाने का फैसला, तो कोई राजनीतिक दल करेगा। जहां तक भाजपा का सवाल है हम इस मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बनाकर दलगत राजनीति के अखाड़े में नहीं जाना चाहते।*

माया: *आपके इस फैसले से क्या आपके और विश्व हिंदू परिषद के संबंधों में दरार नहीं आयेगी?*

वाजपेयी: *विश्व हिंदू परिषद से इस बात को लेकर दरार पैदा होने का सवाल ही नहीं। वे स्वयं इस राय के नहीं कि इस मुद्दे को लेकर वोट मांगे जायें और वोटों के अखाड़े में यह मामला घसीटा जाये। वह तो यह भी आशा करते हैं कि अन्य दल मुसलमानों को समझायें कि उन्होंने जो*

रवैया अपनाया है, वह न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है।

माया : *शहाबुद्दीन ने तो इसी बात पर अपनी इंसाफ पार्टी बना ली है। यदि उन्होंने अपना रवैया न बदला, तो क्या भाजपा निर्णय बदलने को बाध्य न हो जायेगी ?*

वाजपेयी : *शहाबुद्दीन और उनकी इंसाफ पार्टी क्या करेगी, मैं नहीं जानता। हमारा रवैया उनके दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं है। किंतु यदि हमारे दृष्टिकोण की कोई आलोचना करेगा, तो उसका हम समुचित उत्तर देंगे। मगर हम श्रीराम का नाम लेकर वोट नहीं मांगेंगे।*

माया : *रामजन्मभूमि विवाद के हल के लिए क्या न्यायालय का निर्णय आप स्वीकार करेंगे ?*

वाजपेयी : *हमने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास करके इस मांग का समर्थन किया है कि रामजन्मभूमि स्थल हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यह शताब्दियों से हमारा पावन स्थल रहा है। किंतु न्यायालय का निर्णय न मानने की कोई घोषणा मैंने कभी नहीं की। जैसाकि हाल में एमजे अकबर ने उप्र के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से दूरदर्शन पर साक्षात्कार के दौरान कहा। मुझे तो शिकायत है कि शाहबानो केस में स्वयं केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं माना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसे मामलों में जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हों, न्यायालय के फैसले को मनवाना कठिन होगा।*

माया : *हाल में जो एकजुट अभियान विपक्ष ने चलाया है, क्या उससे आपको वाम और दक्षिण के मध्य बेहतर संबंधों की संभावना नजर आती है ?*

वाजपेयी : *ये शब्द भारतीय संदर्भ में अर्थहीन हैं। शोषण के हम विरुद्ध हैं। सामाजिक सवालों पर हम सुधारवादी हैं। इसलिए भाजपा को दक्षिणपंथी कहा जाये और कुछ लोग वामपंथ का ठेका ले लें, यह तो राजनीति का सरलीकरण है।*

माया : *क्या भाजपा और कम्युनिस्ट जनता दल के दो हाथ नहीं हो सकते ?*

वाजपेयी : *उनके साथ हमारा तालमेल नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय मोर्चा उनसे तालमेल करता है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट आपत्ति कर रहे हैं।*

माया : *क्या लोकसभा से सामूहिक इस्तीफों व भारत बंद के बाद भी भाजपा का कम्युनिस्टों के मध्य भावी संपर्क का मार्ग नहीं खुला है ?*

वाजपेयी : *जी नहीं। हम संसद के अंदर सहयोग करते रहे हैं। आगे भी करेंगे। संसद के बाहर उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं।*

माया : *भारत बंद में तो आप लोगों ने सहयोग किया है ?*

वाजपेयी : *वह तो संपर्कविहीन संघर्ष था।*

—रंजना कक्कड़

को होगा, सबसे अधिक हानि कांग्रेस को होगी और कुछ लाभ भाजपा को होगा। यदि तालमेल नहीं होता, तो सबसे अधिक लाभ कांग्रेस का होगा, सर्वाधिक हानि जनता दल को होगी और कुछ हानि हमको होगी। तालमेल का होना न होना हमारे लिए कम अंतर पैदा करता है। किंतु जनता दल और कांग्रेस के लिए फर्क जमीन-आसमान का हो जाता है।"

उल्लेखनीय है कि इस तालमेल का सबसे कम प्रभाव वामपंथ पर पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रभाव क्षेत्र न सिर्फ यहां से बहुत दूर पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में सीमित है, बल्कि वहां उनका वर्चस्व भी सर्वमान्य है। चूंकि वामपंथ कुछ विशेष खोने और पाने की स्थिति में नहीं है इसीलिए उसने यह धमकीपूर्ण रवैया अपनाया है कि यदि जनता दल ने भाजपा से तालमेल किया, तो वामपंथ उसका विरोध करेगा।

वामपंथ की धमकी : वामपंथ का यही रवैया पर्यवेक्षकों व विपक्षी नेताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। जनता दल महासचिव शरद यादव के अनुसार, "तालमेल कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वामपंथ १९६७, १९७२ और १९७७ में चुनावी तालमेल कर चुका है। १९६७ में तो तत्कालीन जनसंघ के साथ मिलकर उसने कुछ राज्यों में बनी संविद सरकारों में भागीदारी भी की थी।" जनता दल की राष्ट्रीय अभियान समिति के सयोजक जार्ज फर्नांडीस ने जोड़ा, "दो वर्ष पूर्व हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वामपंथी पार्टियों ने न केवल लोकदल-ब के साथ गठजोड़ किया, बल्कि चार दलों—लोकदल-ब, भाजपा, भाकपा और माकपा के झंडों तले चुनाव प्रचार भी किया। इसी तरह गत तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने जब मुस्लिम लीग से तालमेल किया, तो मार्क्सवादी पार्टी ने उसका दामन थामने में कोई कोताही नहीं की। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगुदेशम-भाजपा गठजोड़ के बावजूद वामपंथियों ने एकजुटता से परहेज नहीं किया। और तो और १९८८ में राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मार्क्सवादियों को जितने मतों की दरकार थी, उसके लिए उन्होंने यह व्यवस्था की कि भाजपा के फाजिल मत तेलुगुदेशम उम्मीदवार के खाते में चले जायें और इस प्रकार तेलुगुदेशम के बचे वोट उसे प्राप्त हो जायें।"

इसी प्रकार मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति में भाकपा का मजदूर संगठन एटक, माकपा की सीटू और भाजपा की बीएमएस शामिल है। जाहिर है, कोई सीमित अधिकारों के लिए साझा संघर्ष चला सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब देश बर्बाद हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, तो चुनावी तालमेल के लिए शर्तों की बंदिश क्यों ? इसी प्रकार कुछ समय पूर्व लोकसभा से सामूहिक निर्णय का फैसला हुआ और सामूहिक प्रेस कांफ्रेंस हुई, तो ऐसा सौहार्द्रपूर्ण माहौल बना कि वहां नंबूदिरीपाद को पंडित नंबूदिरीपाद और अटल बिहारी वाजपेयी को कामरेड वाजपेयी का नाम दिया गया। यदि लोकसभा में सामूहिक इस्तीफे देकर बाहर आया जा सकता है, तो लोकसभा के भीतर जाने के लिए संघर्ष और तालमेल क्यों नहीं हो सकता ? ऐसे में यदि कोई तालमेल से मुंह मोड़ने की तर्कहीनता पर उंगली उठाता है, तो गलत नहीं।

वैसे दिग्गजों का मानना है कि बात तर्कहीनता की नहीं, एक सोची समझी रणनीति और दूरगामी लक्ष्यों की है। वामपंथ की वर्तमान कूटनीति एक ओर, जन्मजात शत्रु भाजपा पर लगाम लगाने की है, तो दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों को बिदकने-भड़कने न देने और अपनी शोषित-वंचित समर्थक छवि बनाये रखने की है। वामपंथ का मानना है कि अल्पसंख्यकों के वोट उनके अपने शासित राज्यों में तो काफी तादाद में हैं ही, देश के अन्य भागों में भी—विशेषकर उन २६५ सीटों पर जहां उनकी खासी तादाद है—उनके वोट निर्णायक हो सकते हैं।

भाजपा के प्रति लचीला रुख : एम फारूकी

किंतु जनता दल विचारक सुरेंद्र मोहन इस तर्क से असहमत हैं। उनके अनुसार, "नंबूदिरीपाद के वर्तमान रवैये से लगता है कि वे हिंदू संप्रदायवाद और मुस्लिम संप्रदायवाद में भेद रखते हैं। भाजपा से तालमेल होने से मुस्लिम जनाधार खिसक जायेगा इसे भी वे स्वीकारते नहीं। मुसलमान को भी कुव्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि उतना ही सालता और खलता है जितना कि किसी हिंदू या ईसाई को। उसका असंतोष अभिव्यक्त हो सकता है और कांग्रेस के खिलाफ वोट भी दे सकता है। किंतु तब जब उसे विश्वास हो जाये कि विपक्ष जीतनेवाला है और जीत की संभावना सीटों के तालमेल से ही बनती है।"

तालमेल पर प्रश्नचिह्न : भाजपा चुनावों में हिंदू कार्ड भले ही न खेले, किंतु महाराष्ट्र में उसने शिवसेना के साथ जो गठजोड़ किया है, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जो रवैया अपनाया है, अल्पसंख्यक आयोग व संविधान की धारा ३७०—जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है—की समाप्ति की जो मांग की है, उसने वामपंथ को ही नहीं, स्वयं जनता दल को सांसत में डाल दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुद्दे पर न

केवल जनता दल की महाराष्ट्र इकाई में ही मतभेद है, बल्कि उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हालांकि, मधु दंडवते व जार्ज फर्नांडीस जैसे नेता वहां भी तालमेल के पक्षधर हैं। कदाचित हाल के भारत बंद में भाजपा-शिवसेना के असहयोग के कारण महाराष्ट्र में उसकी विफलता ने पुनर्विचार के लिए उन्हें विवश किया है। अतः यह कहना ज्यादा उचित होगा कि असलियत जो भी हो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान विषम माहौल में चुनावी तालमेल हो पायेगा?

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि दोनों (वामपंथी और भाजपा) में झंझट का कारण सत्ता में भीतर अथवा बाहर से साझेदारी और वर्चस्व को लेकर है। यद्यपि औपचारिक रूप से भाजपा ने बराबर यह ऐलान किया है कि विपक्षी सरकार राष्ट्रीय मोर्चे की होगी, जिसका वह घटक नहीं है। किंतु इसमें भागीदारी की उनकी लालसा की झलक उनके पालमपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में स्पष्टतया दिखायी देती है। प्रस्ताव के अनुसार, "लक्ष्य १९९० की लोकसभा में भाजपा के लिए इतने स्थान प्राप्त करना है, ताकि चाहे वह सत्ता में रहे या बाहर रहे भारतीय राजनीति के एक स्थिर केंद्र बिंदु के रूप में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सके।"

विवशताएं : वर्तमान माहौल की भी अपनी विवशताएं हैं। वामपंथी तालमेल से परे रहकर राजीव समर्थक छवि पेश नहीं करना चाहेंगे। दूसरे, उन्हें अपनी राज्य सरकारों—पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा—की भी चिंता है, जिसके खिलाफ केंद्र और कांग्रेस दोनों का तेवर आक्रामक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी मुख्यधारा से अलहदगी उनके लिए महंगी साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त वाम-भाजपा के युद्ध का शोर सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक कम। सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों के प्रभाव क्षेत्र अलग-अलग हैं। सीधी मुठभेड़ की संभावना बिहार तथा उप्र के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में है और वह भी भाकपा से अधिक है, माकपा से बरायेनाम। कदाचित इसीलिए भाकपा ने हाल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाजपा और तालमेल के प्रति अपेक्षाकृत अधिक लचीला और व्यावहारिक रवैया अपनाया है। इसी के तहत गत २५ सितंबर को दिल्ली में देवीलाल हीरक जयंती समारोह की विशाल रैली में यद्यपि माकपा ने शिरकत नहीं की, किंतु भाकपा सचिव एम फारूकी न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि उन्होंने रैली को संबोधित भी किया।

तालमेल के संबंध में जनता दल के नेताओं का मानना है कि वाम-दक्षिण की तमाम बयानबाजी अपने-अपने अहं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने के लिए है। राष्ट्रीय मोर्चे के एक पदाधिकारी ने 'माया' को बताया कि तालमेल की बात शुरू होते ही इस बात पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया कि वामपंथी की किसी प्रकार सार्वजनिक रूप से न तो हेठी ही हो और न अपने कार्यकर्ताओं के सामने उसे शर्मिन्दगी ही उठानी पड़े। इसी के चलते भाजपा के साथ तालमेल की बात चलानेवाले देवीलाल के अतिउत्साह को नियंत्रित करने का निर्णय भी लिया गया। उक्त सूत्र के अनुसार 'टैक्ट, फैक्ट और एक्ट' (रणनीति, यथार्थ और कार्रवाई) की त्रिमुखी रणनीति के तहत विश्वनाथ प्रताप सिंह तालमेल के समूचे मुद्दे को समुचित, संतोषजनक और सफल ढंग से सुलझाने में लगे हैं।

लक्ष्य एक है : तालमेल की सुदृढ़ सीमेंट राजीव हटाओ विरोधी मुहिम है, जिससे भाजपा व वामपंथ दोनों ही जुड़े हुए हैं। जनता दल के वरिष्ठ नेता मधु दंडवते के अनुसार वे इस तथ्य से भी सहमत हैं कि सत्ता के दावेदार न तो वामपंथी हैं और न भाजपा। कारण, दोनों में से कोई भी ५० प्रतिशत से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। निस्संदेह राजीव गांधी सरकार को चुनौती देने और सत्ता परिवर्तन करनेवाली प्रमुख शक्ति राष्ट्रीय मोर्चा है, जिसका जनता दल एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटक है।

वामपंथ और भाजपा की जंग उन निर्वाचन क्षेत्रों में है, जहां मुठभेड़ राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल और कांग्रेस के बीच नहीं है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे हैं, जहां एक का पलड़ा दूसरे से कहीं अधिक भारी है। मसलन, मप्र में यदि वामपंथी उम्मीदवार खडा हो और पश्चिम बंगाल में भाजपा का, तो चुनाव परिणामों पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़नेवाला है। लालकृष्ण आडवाणी का तो यहां तक मानना है कि यह तीसरा उम्मीदवार विपक्ष को लाभान्वित करेगा, क्योंकि वोट वह कांग्रेस का ही काटेगा।

आक्रामक तेवर : ज्योति बसु

फिलहाल प्रतीक्षा और दबाव की रणनीति वाम और भाजपा दोनों ही अपना रहे हैं। मार्क्सवादी पार्टी ने तालमेल के बारे में कोई निश्चित निर्णय अपनी आगामी १५-१६ अक्तूबर को होनेवाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक टाल दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार हाल की पोलित ब्यूरो की बैठक में तालमेल के मुद्दे पर नंबूदिरीपाद के नेतृत्ववाले केरल कैंप और ज्योति बसु की अगुवाईवाले पश्चिम बंगाल कैंप में गंभीर मतभेद रहा। इस अंतराल में जनता दल और भाजपा के मध्य स्थिति और स्पष्ट होगी तथा लोकसभा चुनाव के बारे में तय तारीख की घोषणा या अंदाजा होगा। इसी दौरान विपक्ष और कांग्रेस की हैसियत का और खुलासा होगा। साथ ही, वामपंथ द्वारा संप्रदायवाद विरोधी और राम जन्मभूमि मुद्दे के समुचित हल को लेकर जारी अभियान के प्रति जनता दल का रुख भी स्पष्ट होगा। इस समूचे राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी तालमेल संबंधी फैसले में माकपा के लिए सहायक होगी।

भाजपा का संकट : वैसे वामपंथ के विपरीत भाजपा का अब तक का रुख तालमेल समर्थक और चटपट समझौते का रहा है। किंतु हाल की बंबई बैठक के दौरान राष्ट्रीय नेताओं और राज्य इकाइयों के मध्य उभरे मतभेदों ने एक नयी समस्या खड़ी कर दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राज्य के नेता केंद्रीय नेतृत्व से जवाबतलब कर रहे हैं कि वह क्यों कम सीटों पर अपनी सहमति दे रहा है। राज्यों के नेता न केवल अधिक सीटों का आग्रह कर रहे हैं, बल्कि कौन सी सीटें लड़ें, इसका भी। मप्र, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, दिल्ली की इकाइयां तालमेल के प्रति फिलहाल बहुत उत्सुक नहीं हैं। मप्र में भाजपा जनता दल को ५-६ सीटों से अधिक देने की पक्षधर नहीं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व अधिक सीटें देने के पक्ष में है। इसी तरह राजस्थान व गुजरात की भाजपा इकाइयां १६-१६ सीटों, हिमाचल की ४ में से ३ व दिल्ली की ७ में ६ सीटो पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है।

भाजपा उप्र, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में १६९ सीटों पर जनता दल के वर्चस्व को स्वीकार करती है और स्वयं इन क्षेत्रों से ४० सीटें चाहती है। इसी प्रकार जनता दल मप्र, दिल्ली, हिमांचल, और चंडीगढ की ५२ सीटों पर भाजपा का वर्चस्व मानती है। भाजपा इनमें ४२ सीटों पर लड़ना चाहती है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अभी भी राज्य इकाइयों को समझा-बुझाकर जनता दल से व्यापक तालमेल के लिए प्रयासरत है। किंतु गाडगिल का मानना है, "यदि भाजपा को तालमेल से लाभ नजर नहीं आया, तो वह अकेले चुनाव मैदान में उतरने में न देर करेगी, न संकोच। हां, अगर इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सूचना आ गयी, तो सोचना आपसे आप बंद हो जायेगा।"

दूसरी ओर, विपक्षी पार्टियों के बीच तालमेल न हो, इसके लिए कांग्रेस भी एड़ी-चोटी का पसीना बहा रही है। कभी भाजपा पर संप्रदायवाद का ठप्पा लगाकर, तो कभी वामपंथ पर अवसरवादी गठजोड़ का। इसलिए ऊंट अंततः किस करवट बैठेगा, यह कहना फिलहाल कठिन है। लेकिन २५ सितंबर की दिल्ली रैली में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने का विपक्षी आह्वान और अपने पक्ष में दिनोदिन बनते-बढ़ते माहौल ने उसके हौसले कुछ ऐसे बुलंद किये हैं, कि अधिकांश नेता झंझट से इनकार न करते हुए भी गर्मजोशी से कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सारे गिले-शिकवे भूलकर विपक्ष एकजुट हो कांग्रेस के खिलाफ रणभूमि में उतर आयेगा।

—रंजना कक्कड़

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

रश्मि
Rashmi
Rashmi
ZAFRANI PATTI
Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
CHEWING TOBACCO
SATYAPAL SHIVKUMAR
355, NAYA BANS, DELHI-110006 (INDIA)

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब,

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद,
वाह! क्या लाजबाब.......

रश्मि ज़र्दा

सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006

BLISS/DEL

(वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

जोड़ों का दर्द ख़ूब ?

आराम दिलाए 'मूव'

30 Gm
moov
moov
moov
moov
moov
Ayurvedic Medicine
EXTERNAL USE ONLY

घुटने के जोड़ का दर्द?
पीठ के जोड़ों का दर्द?

उम्र की वृद्धि से या अधिक कठिन परिश्रम करने से आपके शरीर के विभिन्न जोड़, विशिष्ट रूप से आपके घुटने और आपकी पीठ, दर्द के क्षेत्र बन जाते है. यह दर्द, जोड़ों के बीच में चिकने तरल की कमी से होता है. जोड़ों में रगड़ होने से आपको पीड़ा और बेचैनी होने लगती है.

जड़ तक पहुँचने वाला

'मूव' में हैं बहुत गाढ़े प्राकृतिक परिवर्तनशील तेल, जो आपकी त्वचा से होकर जोड़ों में दर्द की जड तक पहुँच जाते हैं

जल्द असर करने वाला

'मूव' अपने प्राकृतिक तेलों से – जो शक्तिदायक लाभकर रस है, तुरन्त ही रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं, चिकना तरल वापस आ जाता है. आपको मिलता है जल्द आराम

अधिक समय तक आराम दिलाए

'मूव' के मलते ही, उसका बेजोड़ फार्मूला वाला बेस प्राकृतिक तेलों का स्थिर प्रवाह करता है, जो प्रभावित क्षेत्र को अधिक समय के लिए गर्म रखता है, बिना त्वचा को जलन पहुँचाते हुए.
दर्द बिना की गतिशीलता लौट आती है और आप फिर आराम से चल-फिर सकते है.

उत्तम निवारक, बेहद असरकारक **'मूव'**

जोड़ों का दर्द निवारक

PARAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
Jitendra Chambers, Ashram Road, AHMEDABAD 380 014

पायलटों की भगदड़

विमान सेवा के पायलटों (चालकों) के बारे में यह मिथक बन चुका है कि उनकी नौकरी, उनका वेतन और उनकी जीवनचर्या—सब कुछ शानदार होता है। लेकिन हाल ही ४० शीर्ष पायलटों द्वारा इंडियन एयरलाइंस (आईए) की सेवा से त्यागपत्र देकर विदेश चले जाने से जहां पायलट सेवा के बारे में प्रचलित मिथक टूटने लगा है, वहीं इंडियन एयरलाइंस की पायलट सेवाएं भी सवालों के घेरे में आ गयी हैं। इंडियन एयर लाइंस में कुल ५७१ पायलट हैं और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से ४० पायलटों के पलायन कर जाने के बाद अब और पायलट उनका अनुसरण नहीं करेंगे। इसका एक वजनदार कारण है—विदेशी विमान सेवाओं में अधिकतम वेतन का प्रलोभन। यह प्रलोभन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भारत में भारतीय पायलटों को आठ से नौ हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलता है, वहीं सऊदी अरब की विमान सेवा उन्हें एक लाख, ४० हजार रुपए प्रतिमास वेतन देने को तैयार है। एयर साइप्रस ने तो पायलटों को एक लाख, ६५ हजार रुपए प्रतिमास तक वेतन देने की पेशकश कर दी है।

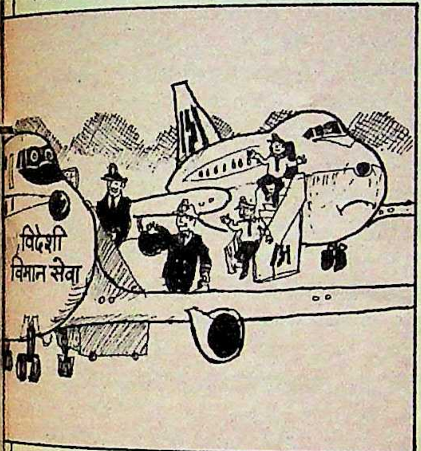

कनाडा और अमरीका जैसे देश भी भारत जैसे देशों के पायलटों को आकर्षित करने के लिए आप्रवासी एवं अन्य कानूनों में ढील देने पर विचार कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में तैनात अधिकांश यूरोपीय एवं अमरीकी पायलट स्वदेश लौट चुके हैं और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से कार्यरत अधिकसंख्य पायलट सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पायलटों की कीमतें और मांग बढ़ गयी है। अनेक मुल्कों ने हाल ही अपनी विमान सेवाओं का विस्तार भी किया है और उनके पास प्रशिक्षित पायलटों का अभाव भी है। जाहिर है कि भारत के और भी पायलट अधिक वेतन के लालच में विदेश जा सकते हैं। लेकिन वहां स्थायित्व न होने का जोखिम भी है, जिसकी भरपाई बेहद ज्यादा वेतन देकर करने की कोशिश की जाती है। सवाल उठता है कि क्या भारतीय पायलट अधिक वेतन के प्रलोभन से विदेश जा रहे हैं या इसके अन्य कारण भी हैं? एक पायलट के प्रशिक्षण पर दो लाख रुपए से अधिक का खर्च आता है। प्रशिक्षकों और निरीक्षक पायलटों के मामले में वैसे भी स्थिति संकटपूर्ण है। दिल्ली, बंबई, मद्रास व कलकत्ता के करीब १५ प्रतिशत पायलटों के विदेश चले जाने से अकेले कलकत्ता में एक रिपोर्ट के अनुसार एक सप्ताह में कम-से-कम २० उड़ानें रद्द हुईं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या अपने बहुमूल्य पायलटों को गंवाकर करोड़ों रुपए की क्षति उठाने का जोखिम उठा सकती है? एक पायलट ने बताया, "यदि यह सुविधा पहले दरपेश होती, तो भगदड़ पहले ही मच जाती।" भगदड़ का यह वक्त आईए के लिए बड़ा महंगा साबित हो रहा है। कारण, उसने हाल में पांच ए-३२० एयरबसें चालू की हैं और अगले दो वर्षों में वह २६ और एयरबसें चलायेगा।

पायलटों की मौजूदा कमी की जिम्मेदारी स्वयं पायलट सातवें दशक में जारी एयरलाइंस की भर्ती नीति के सरमाथे मढ़ते हैं। १९७३ की श्रमिक समस्याओं के दौरान तत्कालीन आईए अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल पीसी लाल ने यह कहकर नयी भर्तियों पर पाबंदी लगायी थी कि आईए में जरूरत से ज्यादा पायलट मौजूद हैं। छह वर्ष बाद १९७९ में पायलटों की पुनः भर्ती शुरू तो हुई, किंतु बहुत छोटे पैमाने पर। विडंबना है कि उसी समय आईए ने बड़े पैमाने पर अपना विस्तार कार्यक्रम चलाया, नये मार्ग शुरू किये और अपनी पुरानी उड़ानों में इजाफा किया, लेकिन अपेक्षित संख्या में पायलटों को तैयार नहीं किया।

पायलटों में असंतोष: असली समस्या तो अगले वर्ष तब खड़ी होगी, जब २२ बोईंग ७३७ के लिए लगभग ११० पायलटों की दरकार होगी, किंतु तब न्यूनतम उड़ान घंटों के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार मात्र ४०-५० पायलट और सहपायलट ही उपलब्ध होंगे। इन्हीं सहपायलटों और पायलटों को एवरो और फोकर-२७ चलाने का अनुभव है। सहपायलटों में से उन लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो २५०० उड़ान घंटे पूरे कर चुके हैं। इन पायलटों और सहपायलटों को एवरो और फोकर विमान-चालन का अनुभव भी नहीं है, क्योंकि ये विमान अब प्रचलन में नहीं हैं। नतीजतन, सुरक्षा और प्रशिक्षण के मामले में समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत बोईंग विमान के संचालन के पूर्व ४५०० उड़ान घंटों का अनुभव आवश्यक है। आईए के प्रबंध निदेशक आर प्रसाद का मानना है कि प्रबंधक स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं, किंतु पायलटों में व्याप्त असंतोष को देखते हुए इसे उनकी खुशफहमी कहा जा सकता है।

आईए पायलटों का मत है कि उन्हें प्रतिमास बहुत कम वेतन-६००० से ७००० रुपए और बरायनाम भत्ते आदि मिलते हैं। उनके अनुसार, पड़ोसी देशों में भी बेहतर वेतन-भत्ते उपलब्ध हैं। मसलन, पाकिस्तान में पायलट को आईए पायलट से कम-से-कम दोगुना अधिक वेतन मिलता है। इसी प्रकार पाकिस्तानी पायलटों को जहां साज-सामानयुक्त मुफ्त मकान, टेलीफोन, एयरकंडीशंड यातायात और पूरे परिवार के लिए चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध है, वहीं भारत में पायलट को मकान-भत्ते की शक्ल में १००० रुपए प्रतिमाह (यह रकम हाल में बढ़ी है जो पहले ४०० रुपए ही थी), थोड़ा सा टेलीफोन भत्ता और यातायाता के लिए खटारा एम्बेसडर कार उपलब्ध है। नेपाल एयरलाइंस के पायलट तक की इससे बेहतर स्थिति है। वहां के वरिष्ठ पायलट को १४००० रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। श्रीलंका एयरलाइंस के पायलट को भारतीय पायलट से तीन गुना अधिक वेतन मिलता है।

इंडियन एयर लाइंस के पायलटों की कसक तब और गहरी हो उठती है, जब वे एयर इंडिया (एआई) के पायलटों से अपनी तुलना करते हैं। दोनों का वेतन ढांचा समान है, किंतु भत्तों आदि में भारी अंतर है। एआई पायलट को वेतन, भत्ते आदि के रूप में २५ हजार से ३० हजार रुपए मिलते हैं, जबकि आईए पायलट को ५ से ६ हजार रुपए मिलते हैं। आईए के पायलटों का यह भी कहना है, "हम अपने घर से जीप से हवाई अड्डे या होटल जाते हैं, जबकि एयर इंडिया के पायलट एयरकंडीशंड कारों से।"

अधिकांश आईए पायलटों का कहना है कि वे भत्तों की मदद से अपना गुजारा करते हैं। उन्हें पांचसितारा होटलों में मुफ्त आवास और भोजन के लिए नकद राशि मिलती है। एक कैप्टन ने 'माया' को बताया, "हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि वह मुफ्त मिलता है और खाना होटल के बाहर खाते हैं जिससे पैसा बच सके। इस तरह हम मकान भाड़े का प्रबंध करते हैं।"

बेहतर वेतन की मांग: आईए पायलट बेहतर वेतन की अपनी मांग को जायज करार देते हुए कहते हैं कि उनका काम विशिष्ट है और उन्हें बेहद तनाव और दबाव में काम करना पड़ता है। हर छह महीने बाद पायलट को डाक्टरी जांच से गुजरना पड़ता है। एक पायलट का कहना था, "यदि मुझे मधुमेह या उच्चरक्तचाप हो जाये, तो मैं अक्षम करार दिया जाऊंगा। उस हालत में मुझे २ लाख रुपए देकर या तो सेवामुक्त कर दिया जायेगा या बेहद कम वेतनवाला प्रशासनिक काम सौंप दिया जायेगा। मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल सकता क्योंकि पायलट के सिवा मुझे अन्य

किसी कार्य का ज्ञान नहीं है।

आईए पायलटों को यह भी शिकायत है कि उनकी हैसियत हाल में कम हुई है। प्रशासनिक विभाग के अधिकारों में हाल में भारी इजाफा हुआ है, ऐसा मानते हुए बोइंग—७३७ के एक कमांडर कहते हैं, "हमें भीख की तरह अपने बकायों की गुहार लगानी पड़ती है, जबकि एआई पायलटों के बकायों की तुरंत अदायगी हो जाती है।"

इन आरोपों-प्रत्यारोपों के भंवरजाल की जानकारी रखनेवाले यात्रियों में अपनी सुरक्षा की चिंता बढ़ गयी है। उनकी यह चिंता कुछ हद तक जायज भी है। मसलन, इस किल्लत (पायलटों की) के चलते एयरबस—३०० के पायलटों को बोइंग—७३७ में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय नियम और अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच-अदालत के ये सुझाव भी पायलटों में कुंठा भर रहे हैं कि पायलटों को एक समय में एक ही विमान उड़ाना चाहिए। इसके बावजूद खबर है कि ७० से ८० पायलटों द्वारा भी एयरबस और बोइंग—७३७ दोनो प्रकार के विमान चलाये जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उड़ान सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पायलट का तो यहां तक कहना है, "भारतीय जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है।"

अनेक आईए पायलटों का आरोप है कि आईए अब प्रशिक्षण कार्यक्रम में कटौती कर रहा है। पहले बोइंग—७३७ का पायलट १३-१४ वर्ष के अनुभव के बाद एयरबस चालक होता था। अब इस अनुभव अवधि को बेहद कमकर ३ से ७ वर्ष कर दिया गया है।

भगदड़ रोकने के प्रयास : रिपोर्टों से उजागर है कि आईए एयरबस—३२० के पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में कटौती कर रहा है। छह माह की फ्रांस की सामान्य प्रशिक्षण अवधि पांच हफ्ते में सिमिट गयी है। एयरबस—३२० के पायलटों की कमी को मद्देनजर रख फ्रांस ने भारतीय पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए ११ हजार डालर प्रति माह फीस की दर से पायलट मुहैया किये हैं। इन पायलटों को इतनी मोटी रकम देने से भारतीय पायलटों में पर्याप्त आक्रोश-असंतोष है। प्रबंधकों ने इस आशंका से कि कहीं एयरबस पायलट विदेश न चले जायें, उनसे करारपत्र पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की, किंतु यूनियन के दबाव से आईए इसमें सफल नहीं हो सका। पायलटों की भगदड़ को रोकने की गरज से आईए ने सिंगापुर एयरलाइंस से किसी भारतीय पायलट की भर्ती न करने का अनुरोध भी किया है। इसने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से ऐसे तमाम भारतीय पायलटों की सूची मांगी है, जिन्होंने आवेदन किये हैं। आशा है, इससे भगदड़ पर लगाम लगेगी। 'माया' ने जब पायलटों के विदेश पलायन को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के संबंध में आईए कार्यालय से संपर्क किया, तो कोई जवाब नहीं मिला। संभवतः सार्वजनिक संपर्क विभाग इस मुद्दे को गंभीर नहीं समझता। इस संबंध में बोइंग—७३७ के एक वरिष्ठ पायलट की टिप्पणी है, "वे पूरे मामले पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु देर-सबेर उन्हें गंभीर हालात का सामना करना पड़ेगा।"

गंभीर हालात से निजात दिलाने की उम्मीद पायलट रह चुके प्रधानमंत्री राजीव गांधी से की जा सकती है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह बतायी जाती है कि उनके जमाने के उनके करीबी रहे प्रायः सभी पायलट सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में जो पायलट कार्यरत हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है। यह एक मायने में अच्छा भी है, क्योंकि ऊपर की दखलंदाजी के बिना मुमकिन है कि आईए के मसले सुलझ जायें, क्योंकि इस तथ्य से पायलट और आईए के प्रबंधक अच्छी तरह परिचित हैं कि उन्हें साथ-साथ अस्तित्वमान रहना है और एक दूसरे से सहयोग करना है। पायलटों की मांग कितनी ही जायज क्यों न हो, उन्हें यह वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारत अमरीका जैसा धनी देश नहीं है, तथा न तो यहां सऊदी अरब जैसा राजतंत्र है और न ही भारत को पाकिस्तान जैसी विपुल विदेशी सहायता प्राप्त होती है। भारत के पायलट जितना चाहे ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पैर अपने देश की जमीन पर ही टिकाने पड़ेंगे।

—सुधा भाटिया

तितलियों की रंग बिरंगी छटा
दीवारों पर कैद करें.

गुणवत्ता, रंग व सुन्दरता में सर्वोत्तम
साथ ही किफ़ायती भी

अंगूर® एवं चेरी

• लाइम कलर्स • ड्राई डिस्टेम्पर • सीमेंट ऑक्साइड कलर्स

बच्छराज कलर्स (प्रा) लि.
रजि. कार्यालय : मच्छरहट्टा, पटना सिटी-८००००८
दूरभाष : ४२३८९, ४२०९२, ४१११५
शाखा कार्यालय : ११९, सेक्टर ३७, नौएडा-२०१३०१
दूरभाष : [illegible]

mahima/bcpl/89

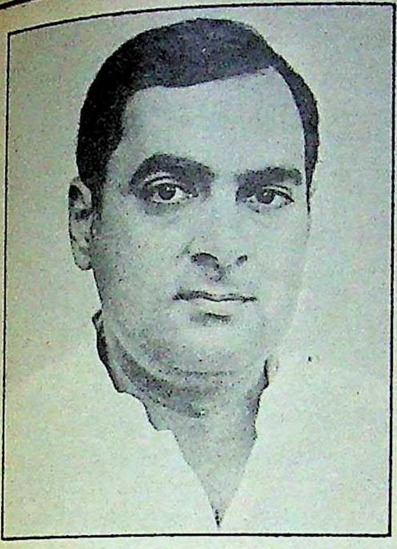

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की प्रगति

जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश एक घनी आवादी वाला प्रदेश है जिसकी लगभग ८७ प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों निवास करती है। और इन ग्रामीण अंचलों में रहने वालों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि योग्य भूमि के सीमित होने और बढ़ती हुई आवादी के कारण कृषि पर दवाव अधिक बढ़ रहा है जिससे रोजगार के अवसर दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता बेरोजगारी से तंग आकर नगर की ओर पलायन भी कर रही है। इसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह महसूस किया कि प्रदेश की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए प्रदेश के कोने कोने में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का जाल बिछा दिया जाये।

इस उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में तीन लाख लघु एवं ५ लाख ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है जो प्रशाधन के अभाव में अभी तक व्यर्थ जा रहा था। स्थानीय कच्चा माल और अपार श्रमिक शक्ति का उपयोग खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्च, १९८८ तक २६४९ समितियां २९५५ संस्थायें लगभग ग्यारह हजार व्यक्तिगत इकाइयों के वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। उनके द्वारा १७८५०.५० लाख का उत्पादन किया गया तथा दो लाख ८१ हजार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। बोर्ड द्वारा सभी मण्डलों में केन्द्र खोले जा रहे हैं। पांच प्रशिक्षण केन्द्र कालाडूंगी, (नैनीताल), प्रतापपुर (इलाहाबाद), खजनी (गोरखपुर), कालपी (जालौन) एवं डालीगंज (लखनऊ) में स्थापित कर प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य ६ प्रशिक्षण केन्द्र भी शीघ्र ही स्थापित किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से ८७-८८ में तीन हजार दो सौ अट्ठानवे व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में १७६१३ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में चौहद हजार ४१ इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इन इकाइयों को कमीशन एवं बैंकों के माध्यम से २४३३ लाख रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पांच लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतनी अधिक संख्या मे इकाइयां स्थापित करने हेतु केवल खादी ग्रामोद्योग आयोग के बजट कर निर्भर नहीं किया जा सकता इसए यह योजना बनायी गयी है कि आयोग के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, हरिजन समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग एवं आदि के द्वारा भी इन इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करायी जायेगी।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यह विशाल कार्यक्रम बनाया गया कि गांधी आश्रम एवं अन्य स्वैच्छिक संगठन जो खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं गांवों तक इन कार्यकर्ताओं की पहुंच है उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाये। इस प्रकार के संगठनों से उद्यमियों के चयन, प्रशिक्षण, कच्चे माल को उपलब्ध कराना है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने विगत दो तीन वर्षों में विशेष रूप से बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब खादी बोर्ड द्वारा संचालित ३८ व्यवसायों से तैयार वस्तुओं का विक्रय प्रदेश के कोने कोने में तो हो ही रहा है साथ ही इसकी वस्तुओं की मांग अब देश के अन्य प्रदेशों में भी होने लगी है। प्रदेश के ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को तब और भी वल मिला जबकि श्रीलंका ने हमारे प्रदेश के हाथ कागज को बहुत सराहा और अब उसका नियमित रूप से क्रय कर रहा है।

रेशम जो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है जिसके ककून का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी में इस समय लगभग एक हजार रुपये है इस उद्देश्य से हमारे प्रदेश में इस समय शहतूत एवं अर्जुन के वृक्षारोपण पर अधिक वल दिया जा रहा है जिसके लिए कपास जैसी संस्था प्रति उद्यमी ९५०० रुपये अनुदान रूप में भी देती है।

हथकरघा उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। पन्द्रह लाख से भी अधिक बुनकर इस उद्योग के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पांच लाख हथकरघों पर लगभग ६०० मिलियन मीटर हथकरघा वस्त्र का उत्पादन वर्ष १९८७-८८ में किया गया था। वर्ष ८८-८९ में ६६० मिलियन मीटर हथकरघा वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में बढ़कर प्रति वर्ष ७०० मिलियन मीटर हथकरघा के उत्पादन का लक्ष्य हो गया है।

हथकरघा निगम १८८ उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से करीब ६४,००० अंगीकृत हथकरघों को सूत उपलब्ध कराकर हथकरघा वस्त्र का उत्पादन कराती है। चालू

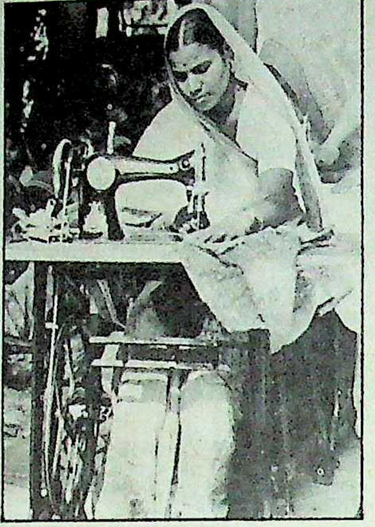

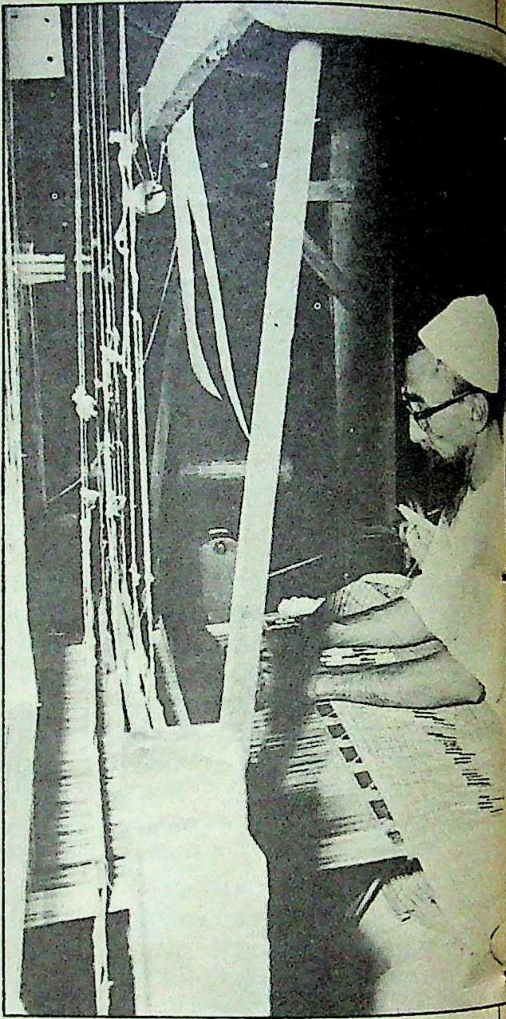

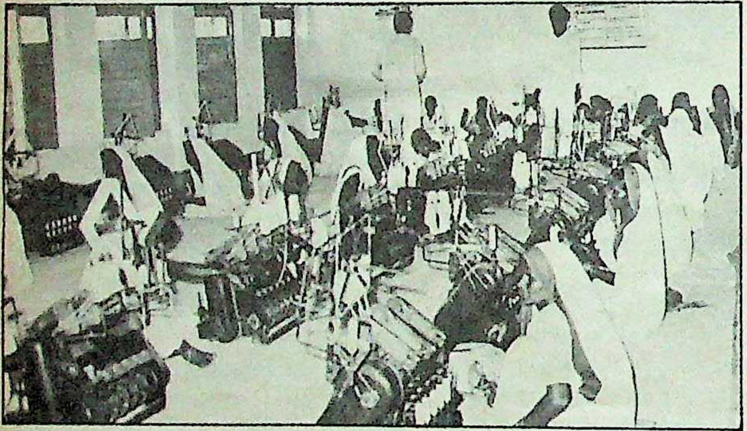

वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा करीब २२.५ करोड़ रुपये मूल्य के यार्न के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिससे ४४ करोड़ रुपये मूल्य का जनता वस्त्र एवं १८ करोड़ रुपये मूल्य का अनियंत्रित वस्त्र का उत्पादन हो सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्र के बुनकरों के लाभार्थ हथकरघा निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना (ऊनी हथकरघा कुमायूं व गढ़वाल मण्डल में प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना के पूरा होने पर १० करोड़ रुपये के हथकरघा ऊनी वस्त्र का व्यापार होने लगेगा।

वाराणसी एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों मे निगम द्वारा सिल्क एवं साड़ियों के उत्पादन में लगे बुनकरों के विकास के लिये १.०८ करोड़ के लागत की परियोजना चलाई जा रही है, परियोजना के पूरे हो जाने पर एक वर्ष में करीब ५.५० करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है।

सहकारिता क्षेत्र के बुनकरों को उत्पादन एवं विपणन से सम्बन्धित सुविधायें यूपिका के द्वारा प्रदान की जा रही है। इस शीर्ष सहकारी संस्था की स्थापना वर्ष १९५२ में की गयी। प्रदेश में स्थापित १२ उत्पादन केन्द्रों एवं प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थापित ७७ बिक्री केन्द्रों के द्वारा सहकारिता क्षेत्र में लगे १६०० प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपिका द्वारा १५ करोड़ रुपये के सूत के वितरण से २५ करोड़ रुपये के मूल्य के हथकरघा वस्त्र का उत्पादन किया गया।

हथकरघा बुनकरों को सस्ते दर पर यार्न उपलब्ध कराये जाने के लिए १७.५ करोड़ रुपये मूल्य के सूत का आयात किया गया है इसका वितरण उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम व यूपिका के द्वारा किया जा रहा है।

व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों को ३० हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी एवं टर्म लोन उपलब्ध कराये जाने हेतु ७० बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में बुनकर सेवा शिविर का आयोजन किये जाने हैं। अनुमान है कि ७० बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ष १९८८-८९ के अन्त तक करीब १० करोड़ रुपये का ऋण बुनकरों को वितरित किया गया।

बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में थ्रिफ्ट फण्ड योजना के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक करीब ७० हजार बुनकरों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ भारत सरकार की घोषित नीति के अनुरूप जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना बुनकरों के लिए क्रियान्वित की गयी है। बुनकर बहबूदी फण्ड से भी बुनकरों को राहत पहुंचायी जा रही है। वर्ष १९८८-८९ में करीब ४ हजार बुनकरों को इस कोष से लाभ प्रदान किया गया।

बुनकरों के कार्य में सुधार लाये जाने की दृष्टि से आवास युक्त कार्यशाला योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष १९८८-८९ में करीब २ हजार आवास से सम्बद्ध कार्यशाला का निर्माण किया गया।

बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में जनता वस्त्र योजना भारत सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत इस वर्ष ८८-८९ में १२० मिलियन वर्ग मीटर जनता वस्त्र का उत्पादन हथकरघा निगम व यूपिका द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशा उद्योग, चर्म उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, चूना उद्योग, काष्ठ एवं लौह उद्योग, कुम्हारी, दियासलाई, मोमबत्ती जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री का आदेश अधर में

कांग्रेस-इ अध्यक्ष राजीव गांधी ने बड़े जोरशोर से घोषणा की थी कि इंका मुख्यालय में तैनात महामंत्री तथा दीगर पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आगामी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग चुनाव लड़वायेंगे। राजीव गांधी की इस घोषणा का दिल से स्वागत करनेवालों में इंका के महामंत्री गुलाम नबी आजाद तथा उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव थे। उसी समय यह कहा गया था कि चूंकि गुलाम नबी आजाद अपने लिए कोई सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं ढूंढ़ पाये, इसलिए उन्होंने ही यह सुझाव राजीव गांधी के पास भेजा था।

राजीव गांधी

कांग्रेसाध्यक्ष राजीव गांधी की इस घोषणा का सबसे पहले खुला विरोध पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गनी खां चौधरी ने किया। इसके बाद राजीव गांधी ने गनी खां को मालदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की विशेष अनुमति प्रदान कर दी। गनी खां का तर्क था कि चूंकि वे मालदा के पूर्व नवाब हैं, इसलिए वहां से उनके अतिरिक्त कोई और चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं जीत सकता है। जब गनी खां चौधरी को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गयी, तो उसके बाद इंका मुख्यालय में अन्य महामंत्रियों—जैसे वीएन गाडगिल, केएन सिंह, शीला कौल—ने राजीव गांधी से आग्रह किया कि उनको भी चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाये। गुलाम नबी ने इसका विरोध किया, तो उनको साफ तौर पर कह दिया गया कि चूंकि उनके पास कोई चुनाव क्षेत्र नहीं है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। इस पर गुलाम नबी ने काफी सफाई दी, लेकिन उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब गुलाम नबी ने देखा कि राजीव गांधी किसी भी समय अपना पुराना आदेश चुनाव न लड़ने का वापस ले सकते हैं, तो वे कश्मीर घाटी में किसी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को तय करने के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की चिरौरी में लग गये। ऐसा लगता है कि अब गुलाम नबी कश्मीर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

अब पता चला है कि राजीव गांधी ने वीएन गाडगिल तथा केएन सिंह को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। शीला कौल को भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जायेगी। लेकिन अभी तक कौल ने यह तय नहीं किया है कि वे लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अगर कौल लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो कांग्रेसाध्यक्ष के आदेश के कारण नहीं, बल्कि अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से नहीं लड़ेंगी। लखनऊ से उनकी जगह उप्र की शिक्षामंत्री स्वरूपकुमारी बख्शी, जो नेहरू परिवार से जुड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे शीला कौल यह चाहती हैं कि उनकी पुत्री दीपा कौल चुनाव लड़ें। कुल मिलाकर कांग्रेसाध्यक्ष राजीव गांधी ने अपने उस आदेश का अनुपालन स्थगित-सा कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि इंका का कोई भी महामंत्री और प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष आगामी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

चीनी कड़वी क्यों और कैसे ?

चीनी के आसमान छूते दामों (साढ़े १३ रु० किलो) ने आम जनता के त्यौहारी स्वाद को कसैला बना दिया था। दीवाली के हर्षोल्लास में मिठास घोलने के लिए सरकार ने राज्य व्यापार निगम के जरिये आयात कराने के नियम तक को बाला-ए-ताक रख २ लाख टन चीनी के आयात के अनुबंधों पर मुहर लगा दी है। १५ सितंबर को जारी किये और १९ सितंबर को खोले गये दूसरे टेंडर के आधार पर सौदा ६ भिन्न कपंनियों से इन दरों पर होने के समाचार हैं:

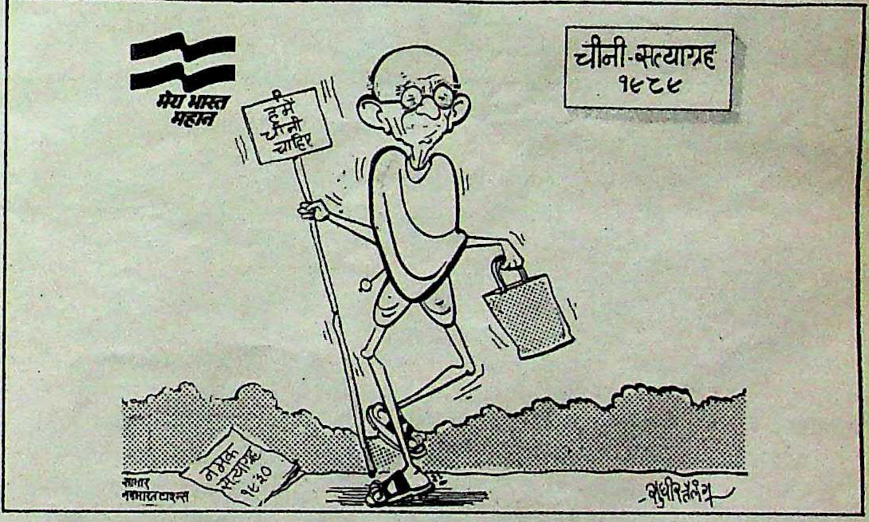

- ● एंग्लोकैमिकल कमोडिटीज—जो फिलिप ब्रदर्स की एक इकाई है—को ८१ हजार मीट्रिक टन चीनी के लिए ५२०.८० डालर प्रति टन की दर पर अनुबंधित किया गया है।
- ● रायंडा कंपनी से १२ से १४ हजार टन चीनी के लिए ५२१ डालर प्रति टन पर सौदा हुआ है।
- ● गिल एंड ड्यूफ्स को ३६ से ४२ हजार टन के लिए ५१७.८० डालर प्रति टन की दर का आर्डर मिला है।
- ● बेल्जियम की फर्म सोसायदे पाउरल से १२ से १४ हजार टन के लिए ५१९.५० डालर प्रति टन पर करार हुआ।
- ● सकडेन को २४ से २८ हजार टन के लिए ५१९.५० डालर प्रति टन पर अनुबंधित किया गया है।

उपर्युक्त दरें भारतीय बंदरगाहों पर उतराई दर के आधार पर हैं और आपूर्ति २० अक्तूबर से पहले होनी है। जानकार सूत्र इस तिथि तक माल पहुंचने को असंभव बताते हैं। अंतिम तिथि पर आपूर्ति तभी संभव हो सकती है, जब माल पहले से लदा, तैयार खड़ा हो जैसा प्रायः होता है। किंतु चूंकि दो सप्ताह से अधिक समय जहाज पर लदे रहनेवाली चीनी की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है, तो वह सस्ते दरों पर बिकती है।

जहां तक सस्ते दरों का सवाल है कदाचित सरकार को उसकी अधिक चिंता न थी। कारण २९ अगस्त को खोले गये पहले टेंडर के लिए कंपनियों ने अपेक्षाकृत कम दरें बतायी थीं। उदाहरणतः रायंडा ने मात्र ४९९.५० अमरीकी डालर प्रति टन की पेशकश की थी। वुडहाउस ड्रेक एंड कं० ने ५०२ डालर प्रति टन, कार्गिल इंकार्पोरेशन ने ५०३ डालर प्रति टन, सुकरा डनरी ने ५१२.६० डालर प्रति टन, ईडीएफ मान लंदन ने ५१९ डालर प्रति टन और स्वयं एंग्लोकैमिकल कमोडिटीज ने केवल ५१४ डालर की पेशकश की थी। इससे भी दिलचस्प तथ्य यह रहा कि पहले टेंडर के दौरान चीनी की अंतरराष्ट्रीय दर लंदन दैनिक मूल्य के अनुसार ५०० डालर प्रति टन थी। दूसरे टेंडर के दौरान यह घटकर ४७५ से ४८० डालर प्रति टन हो गयी थी। घटने-बढ़ने के अनुपात के चलते इस दीपावली की मिठाइयों का दलाली की दुर्गंध से युक्त होना आश्चर्यजनक न होगा। ■

राजनीति की पतंगबाज़ी में किसका पेच लड़ा किसकी पतंग कटी

माया सच से कभी न हटी

राजनीति की पतंगबाज़ी में किसकी पतंग कितनी ऊंची उड़ती है, कौन कैसे पेच लड़ाता है, किसकी पतंग लुटती है... कहने को तो, यह है आम सी बात, लेकिन आज की बात बनती है-कल का इतिहास।

माया सचाई पर से संदेह के पर्दे हटा कर राष्ट्रीय दायित्व निभाती है। माया ने आज के भारत को सचाई का आईना दिखाया। राजनीति के दांवपेच हों या समाज के कुचक्र सभी के लिए दुधारी तलवार... जिसका वार घातक के लिए संहार और आहत के लिए उपचार। माया, जिसने आज के भारत के लिए सच का परचम लहराया।

६० बरसों के अनुभव में पली, भारतीय संस्कारों में ढली...माया।
हिन्दी के पाठकों की एकमात्र ऐसी समाचार पत्रिका
जो हिन्दी में सोचती है और हिन्दी में बोलती है
क्योंकि हिन्दी ही आपकी और हमारी भाषा है।

माया... वह खबर देती है, जिसकी किसी को ख़बर नहीं होती।

सर्वाधिक बिकनेवाली समाचार पत्रिका

माया

जिसमें आज का भारत सिमट आया

Karishma/MAYA/11/9418 H

कोटा का दंगा क्या पूर्व नियोजित था?

कोटा में १४ सितंबर के दंगे के साथ जो सांप्रदायिक आग भड़की है, चुनाव आते-आते क्या पूरे राजस्थान को अपनी लपेट में ले लेगी?

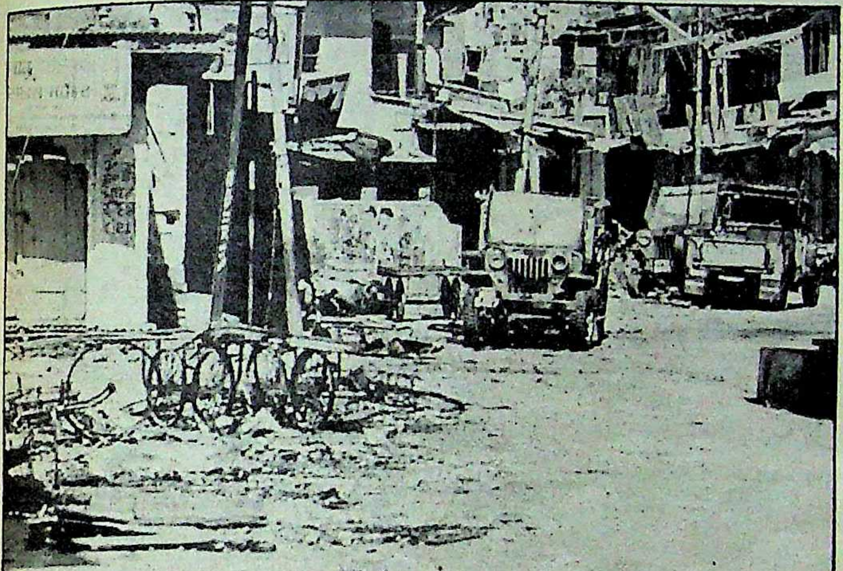

वहशियत की विरासत: घंटाघर के आसपास विनष्ट बाजार

१४ सितंबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोटा में अनंत चतुर्दशी का सालाना जुलूस निकल रहा था। परंपरानुसार शिवजी की बारात जैसा यह जुलूस जब घंटाघर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तकरीबन पौने सात बजे पहुंचा, तो भक्तजनों ने भगवान गणेश की स्तुति के बजाय 'राणा की जय-जय, शिवा की जय-जय' तथा 'इस देश में रहना होगा, तो बंदेमातरम कहना होगा' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिये। भक्तजनों के इन नारों ने मुस्लिम आबादी को चौंका दिया। प्रतिक्रियास्वरूप मुस्लिम मुसाफिर खाने से भी नारे लगने लगे और जुलूस पर पहले चप्पल, फिर पत्थर बरसने लगे और फिर दोनों संप्रदायों की ओर से घातक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल होने लगा।

गौरतलब तथ्य यह है कि जिला प्रशासन ने इस उत्सव के प्रदर्शन के दौरान पिछले तीन सालों से धारदार हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा रखी है। जबकि पहले अखाड़े पट्टे और तलवारबाजी का प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र थे। चश्मदीद लोगों का कहना है कि लाठी-डंडों से सजे छह-सात हजार के इस जुलूस पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने धारदार हथियारों और देशी-कट्टों से हमला बोला था। पथराव व गोलीबारी के कारण जो २०-२५ पुलिसवाले जुलूस के साथ चल रहे थे, डर के मारे एक ओर भाग खड़े हुए। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने पर पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर आंसू गैस छोड़ी गयी। जब भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका, तब पुलिस ने गोलियां भी चलायीं।

पुलिस की खेप आने तक दंगाइयों ने पुलिस के चार वाहनों तथा लगभग चालीस दुकानों को फूंक दिया था। घंटाघर से शुरू हुई हिंसा और आगजनी ने आश्चर्यजनक रूप से एक घंटे में पूरे कोटा शहर को दबोच लिया। दंगाइयों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि सशस्त्र पुलिस के आने पर उस पर भी गोलियां दागीं। इस बीच एक हेड कांस्टेबल बिशनचंद को हिंदू दंगाइयों ने पकड़ कर मुस्लिम दंगाइयों पर गोली दागने के लिए मजबूर किया। उसके मना करने पर बनेठी से उसका सिर फोड़ दिया। बिशनचंद ने घायल होकर गिरने से पहले अपनी राइफल का सेफ्टी लाक लगा दिया। जब दंगाइयों से राइफल नहीं चली, तो उन्होंने बिशनचंद को उठा कर जान से मारने की धमकी देते हुए राइफल चलाने को कहा। बिशनचंद ने मजबूरन राइफल की सारी गोलियों को हवा में चलाकर जान बचायी। पुलिस उप अधीक्षक बंशीधर असवाल को मुस्लिम दंगाइयों ने घेर कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल उप अधीक्षक को दूसरे संप्रदाय के दंगाइयों ने बचा कर आरएसी के जवानों के सुपुर्द किया।

सेना के हवाले: एक घंटे की इस मारकाट के दौरान दंगाग्रस्त क्षेत्र की दुकानें लुटती-जलती रहीं, वहीं मकानों से फायर होते रहे। जुलूस के साथ सुरक्षा की कमान संभाले अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एमएस खान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे रहे। जानकारों के अनुसार कोटा पुलिस अधीक्षक जसवंत संपतराम और जिला कलेक्टर राम लुभाया लगभग सवा घंटे बाद दंगा क्षेत्र में पहुंचे। यहां जिला कलेक्टर पर दंगाइयों द्वारा गोली दागी गयी जो उनके कान के पास से निकली और पुलिस अधीक्षक की पीठ पर पत्थर लगा। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश आदेश दिया।

पुलिस इधर गोलीबारी कर रही थी और उधर दंगाग्रस्त क्षेत्र की बिजली गुल हो गयी। दंगाइयों की और बन आयी। उन्होंने आगजनी और लूट का सिलसिला जारी रखा। दंगाग्रस्त क्षेत्र स्थित बंदूक और कारतूस की दुकान लूट ली गयी। हालत बेकाबू होने पर १०.४५ बजे शहर को सेना के हवाले कर दिया गया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अगले दिन ज्ञात हुआ कि आठ लोगों के शव घटनास्थल से एकत्रित किये गये, जबकि गोली से घायल पांच लोगों ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया था। पहले दिन कुल ७१ लोग घायल हुए थे जिनमें से २० को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था।

१५ सितंबर को मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और गृहमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचे। इस सुबह शहर में सेना का फ्लैग मार्च हुआ, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री ने दंगे से हुए नुकसान का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को बतौर राहत बीस-बीस हजार रुपए देने की घोषणा की और सारे प्रकरण की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का ऐलान किया। इस रस्मअदायगी के बाद मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री जयपुर लौट गये।

'माया' प्रतिनिधि ने स्वयं हादसे के तीसरे दिन कर्फ्यू के दौरान कोटा की गलियों और मोहल्लों के चक्कर लगाये। तनाव, दहशत और रंजिश से भरे लोगों से मुलाकात की। उस वक्त तक दंगे में मरनेवालों की संख्या सोलह हो चुकी थी। साठ से अधिक घायल कोटा के अस्पताल में पड़े थे, जिनमें से आठ की हालत नाजुक बतायी जा रही थी। पुलिस और सेना के अतिरिक्त आरएसी की तेरह कंपनियां दंगे पर काबू पाने के लिए कोटा के लिए रवाना हो चुकी थीं। औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर कोटा शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। छोटे-बड़े पांच सौ से ज्यादा कारखानों की चिमनियों ने धुआं उगलना बंद कर दिया था। दंगाइयों ने अस्सी से ज्यादा दुकानों व मकानों को

बोतल में आम
माज़ा है नाम
माज़ा— माज़ा का स्वाद हमेशा एक जैसा होता है— मज़ेदार
आम— हर आम का स्वाद अलग होता है
maaza
ताज़ा मैंगो माज़ा मैंगो
RADEUS/PE/MM/9-89-HIN
पारले उत्पादन

फूंक दिया था। डोरिया की साड़ी के लिए मशहूर कोटा का कपड़ा बाजार जला हुआ नजर आ रहा था।

कोटा का खास बाजार मुख्य दंगा क्षेत्र घंटाघर के आसपास ही है। मसलन सब्जी मंडी चौराहा, चौथमाता बाजार, पुरानी मंडी, इंदिरा मार्केट, शास्त्री मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन बाजारों में वीरानी, जलती हुई दुकानों का धुआं और दंगे के दौरान इस्तेमाल हुए ईंट-पत्थर नजर आ रहे थे। गुंथे हुए इन बाजारों के अतिरिक्त कोटा के अन्य आबादीवाले इलाके पाटनपोल, कैथूनीपोल, लाडपुरा, गुमानपुरा, छावनी चौराहा इत्यादि भी श्मशानी वीरानी ओढ़े हुए थे। हलचल केवल शांति कायम करने की जिम्मेदारी निभानेवाले फौजियों की नजर आ रही थी। कर्फ्यू पास लेकर चलनेवाले इक्के-दुक्के लोग भी भयभीत थे।

शैतानों का मारा: दंगे में जख्मी लालचंद

'माया' प्रतिनिधि ने दंगे की वास्तविकता जानने के लिए दंगा क्षेत्र की मकबरा बस्ती को चुना जिसके बारे में कहा गया था कि मुस्लिम संप्रदाय के कट्टरपंथी इसी बस्ती से संबंधित थे। इस बस्ती के कामरेड हमीद से मुलाकात हुई जिनको पुलिस तलाश रही थी। 'माया' प्रतिनिधि ने जब हादसे और आरोपों के संबंध में उनसे सवाल किया, तो उनका कहना था—"हादसे के वक्त मैं दरिया में नहा रहा था। लोगों को जब दरिया की तरफ से भागते देखा, तो मैंने उन्हें आवाज देकर भागने का कारण जानना चाहा। पर वे बगैर जवाब दिये निकल गये। मेरे मुहल्ले के लोग जवाब न दें और चुपचाप चोरों की तरह भाग जायें, मुझे बड़ा अटपटा-सा लगा। दरिया से निकल कर जब मैं बस्ती में पहुंचा, तो हाय-तोबा मची हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पूछने पर पता चला कि घंटाघर पर दंगा हो गया है। मेरी बस्ती के लोग उधर मदद के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मेरी बस्ती में लोग मुझे अपना बड़ा समझते हैं, बात भी मानते हैं। उसके बाद गोलियां चलने की आवाज सुनायी पड़ने लगी। घायलों की हमने मदद की, पर उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचा सके। बाद में पुलिस ही लेकर गयी, लेकिन बहुतों ने दम तोड़ दिया।" "मरनेवाले कौन लोग थे?" पूछने पर कामरेड ने कहा, "मैं नहीं जानता कौन लोग थे? हां, कुछ घायल मेरी बस्ती के जरूर थे। वैसे मुझे नहीं मालूम दंगा कैसे शुरू हुआ और कौन जिम्मेदार था। हादसे के दिन मैं शहर में वैसे ही घूमा था, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि दंगे की तैयारियां हो रही हैं!" 'माया' ने हादसे के कारण बताये जानेवाले नारों का जिक्र कर जानना चाहा कि उनकी इन पर क्या प्रतिक्रिया है? कामरेड हमीद का जवाब था— "यह कौन बर्दाश्त करेगा कि 'बंदेमातरम कहना होगा और हिंदू बन कर रहना होगा।' हम यहां मिल-जुलकर रहते आये हैं और रहेंगे पर धर्म-ईमान बदलने की बात करनेवाले लोगों को धर्मनिरपेक्ष जम्हूरियत कैसे बर्दाश्त करेगी?"

हादसे की शुरुआत जुलूस के जिस अखाड़े के प्रदर्शन के साथ हुई थी, उसे 'मन्नाजी चौथमल परथोणे' का अखाड़ा कहा जाता है। इस अखाड़े के पहले गुरु मन्नाजी मुस्लिम थे। मन्नाजी ने अपना उत्तराधिकारी हिंदू चौथमल परथोणे को बनाया। उस्ताद चौथमल ९५ वर्ष के हैं। दंगाग्रस्त क्षेत्र से लगी हिंदू बस्ती में उनका मकान है। 'माया' ने जब उनसे हादसे के बारे में जानना चाहा, तो उनका कहना था—"उस्ताद मन्नाजी तो स्वर्गवासी हो गये और मुझे यह बुरे दिन देखने के लिए छोड़ गये।" उस्ताद अपने रुंधे गले से आगे नहीं बोल सके। 'माया' के सवालों का जवाब दिया उस्ताद के पुत्र बालकिशन ने। उनका कहना था—"हमने कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाये। बस हर-हर महादेव और राणा-शिवा की जय-जय के नारे लग रहे थे। ये नारे तो हम हमेशा ही लगाते हैं।" 'माया' का सवाल था—"पथराव करनेवाले लोग कौन थे?" जवाब था—"पथराव ही नहीं, गोलियां चल रही थीं। कितने और कैसे लोग थे, यह तो हम नहीं देख पाये, पर सब कुछ छतों पर से ही आ रहा था।" "क्या हमला नियोजित था?" "नियोजित न होता, तो इतने पत्थर छतों पर कैसे आते? गोलियां कैसे चलतीं? मारकाट करने के लिए हथियार कहां से आये?"

बंदेमातरम्
असह्य: कामरेड
अब्दुल हमीद

दरिंदगी का अहसास: दंगाइयों की दरिंदगी का अहसास कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल में भर्ती दंगे में घायल लोगों को देख कर होता है। प्रशासन द्वारा दंगे को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद १६ सितंबर की दोपहर ही दो घायल अस्पताल पहुंचे थे। कोटा की केशोपुरा बस्ती के १३ वर्षीय बालक मोहम्मद उस्मान को दंगाइयों की भीड़ ने बड़ी बेदर्दी से घायल किया था। उस्मान के वालिद कोटा की नगरपालिका में भिश्ती का काम करते हैं। दंगे की बहशियत से नावाकिफ बाप, घर से बाहर था, तभी दंगाइयों की भीड़ आयी और उनका घर जलाने की कोशिश की। मां का साथ देते हुए बच्चे ने दंगाइयों को घर जलाने से रोका, तो उन्होंने सरिये से बच्चे का सिर फोड़ दिया। कराहते हुए बच्चे के पिता से 'माया' ने जानना चाहा कि हमला करनेवालों से उनकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी? उनका कहना था—"साहब बदली फिजा का नतीजा है, वरना मुझ गरीब से किसी की क्या दुश्मनी!" बीस साल का जाकिर हुसैन ऐसा ही एक दूसरा घायल था। उसके कूल्हों पर सुबह उस वक्त चाकू मारे गये जब वह शौच के लिए जंगल में बैठा था। जाकिर के मुताबिक चाकू मारनेवाले दंगाइयों ने उसका शिश्न देखा और फिर घायल कर दिया।

अस्पताल में दाखिल हिंदू संप्रदाय के ज्यादातर वे लोग थे जो अनंत चतुर्दशी की शोभा यात्रा में शामिल होने गये थे।

पूर्व संकेत: बताया जाता है कि प्रदेश की गुप्तचर पुलिस ने इस बार कोटा प्रशासन को अनंत चतुर्दशी पर सावधान रहने को कह दिया था। फिर भी प्रशासन उतना चुस्त नहीं रहा। जानकार सूत्रों का कहना था कि चूंकि बारां में डोल का मेला था, इसलिए कोटा से बड़ी संख्या में पुलिस बारां भेज दी गयी थी। पुलिस अधीक्षक जसवंत संपत राम से यह सवाल किये जाने पर कि जब गुप्तचर पुलिस ने पहले से आगाह किया था, फिर प्रशासन क्यों ढीला पड़ा रहा, तब उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर दोनों संप्रदायों में बन रही भावनाओं से तो गुप्तचर पुलिस ने प्रशासन को अवगत कराया था, पर दंगे की संभावनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि शोभा यात्रा के साथ पर्याप्त पुलिस नहीं थी अथवा पुलिस बल हथियारविहीन था।

जिम्मेवार हैं मुख्यमंत्री: भाजपा विधायक ललित किशोर चतुर्वेदी

आरोप-प्रत्यारोप: मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर कोटा के सांप्रदायिक दंगे पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 'सांप्रदायिक दंगे करवाना भाजपा की सुस्पष्ट चुनावी रणनीति है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल जैसे भाजपा के अग्रिम संगठन सहयोग कर रहे हैं।'' मुख्यमंत्री कोटा के दंगे को सुनियोजित करार देते हुए कहते हैं—''वहां आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कायी जा रही हैं।'' जब मुख्यमंत्री से कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गयी, तो उनका कहना था—''ऐसे तत्वों में सामाजिक चेतना जगा कर ही निपटा जा सकता है।'' मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या कोटा के दंगों में बाहरी लोग सक्रिय हैं? उनका जवाब था—''ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।''

राजस्थान में विपक्ष एवं भाजपा के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा—''कोटा के दंगों के लिए कांग्रेस सरकार और शिवचरण माथुर की नीतियां जिम्मेदार हैं।'' इसका खुलासा करते हुए उनका आरोप है, ''मकराना के दंगों में तीन मुसलमानों की हत्या हुई, पर चूंकि हत्यारे कांग्रेसी थे, इसलिए मुख्यमंत्री सद्भावना यात्रा करके घोषणा कर आये कि हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इसी तरह बीगोद के दंगों में भी मुख्यमंत्री ने लुटेरों से कहा था कि लूटी हुई संपत्ति वापस कर दें, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।'' शेखावत का आरोप है, ''कांग्रेस चुनावों को ध्यान में रख कर सांप्रदायिक दंगे करवा रही है, ताकि हाथ से फिसलते मुस्लिम वोटों को रोका जा सके।''

कोटा के निर्वाचित विधायक एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी दंगे के लिए कोटा के पंगु प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने हाड़ौती संभाग की गंभीर स्थिति का हल ढूंढ़ने के बजाय भाजपा व अन्य संगठनों को गाली देना शुरू कर दिया। अपने गैरजिम्मेदाराना बयानों से वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं।

मौजूदा स्थिति: प्रादेशिक राजनेताओं के अतिरिक्त केंद्रीय गृहराज्य मंत्री पी० चिदंबरम ने कोटा आकर खुद जायजा लिया। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी, बोल कर चले गये। उधर कोटा में कर्फ्यू के बावजूद दोनों संप्रदायों में तनातनी जारी है।

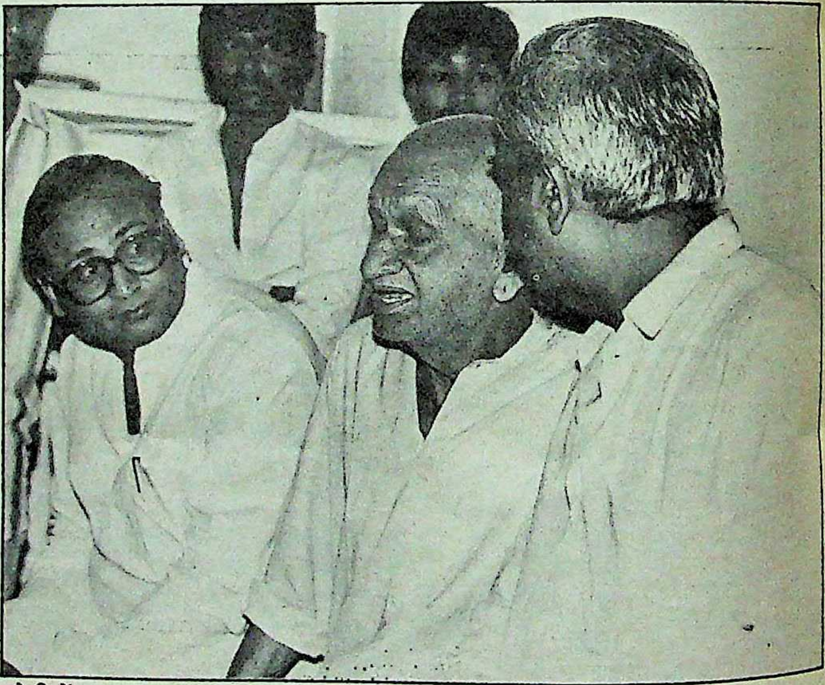

बुरे दिनों का दुख: उस्ताद चौथमल जिनके अखाड़े पर पथराव से दंगा भड़का

१९ सितंबर को कोटा के सांप्रदायिक दंगे के विरोध में कोटा के दस कस्बे बंद रहे। इस दौरान कोटा से २५ किलोमीटर दूर सांगोद कस्बे में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम शिला पूजन के सिलसिले में निकाले जा रहे जुलूस पर किसी ने गोली चला दी। एक व्यक्ति घायल हो गया। इसी कस्बे से जुड़े बालाकुंड में इसी दिन रात में दोनों संप्रदायों ने नारे लगाते हुए मोर्चाबंदी की जिसे पुलिस ने नाकाम किया।

२१ सितंबर को कोटा के विज्ञान नगर में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही शफी मोहम्मद की चाकू गोदकर हत्या कर दी गयी। इस सिपाही को राजकीय सम्मान के साथ दफनाते हुए राज्य सरकार ने उसके परिजनों को डेढ़ लाख की सहायता प्रदान की है। कोटा की बेकाबू हालत देखते हुए केंद्र सरकार ने सीआरपी की तीन कंपनियां भेजने का निर्णय किया है। इनके आ जाने पर कुल २० कंपनियां कोटा में हो जायेंगी। हालात की गंभीरता का पता इससे भी लगता है कि हाड़ौती संभाग के तीनों जिलों, कोटा, झालावाड़ व बूंदी में ३० सितंबर तक धारा १४४ लगा दी गयी थी। भय यह है कि सांप्रदायिकता की यह आंधी समूचे राजस्थान को अपनी लपेट में न ले ले। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला अब राजनीति के पांवों में असर दिखाने लगा है। जात व संप्रदायों की राजनीति करनेवाले नेतागण वोटों के चक्कर में कितना आगे बढ़ जायेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल, राज्य के गृह आयुक्त रामाकृष्णन के अनुसार इन दंगों की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्रनाथ भार्गव करेंगे। इस जांच-कार्य के लिए तीन माह का समय तय किया गया है। उधर कांग्रेसी हलकों में गहलोत विरोधी गुट उन्हें नाकारा गृहमंत्री साबित करने पर तुल गया है, जबकि असलियत यह है कि कोटा के सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए तुरंत सेना बुलाने का निर्णय अशोक गहलोत की ही सूझ थी।

—ओम सैनी

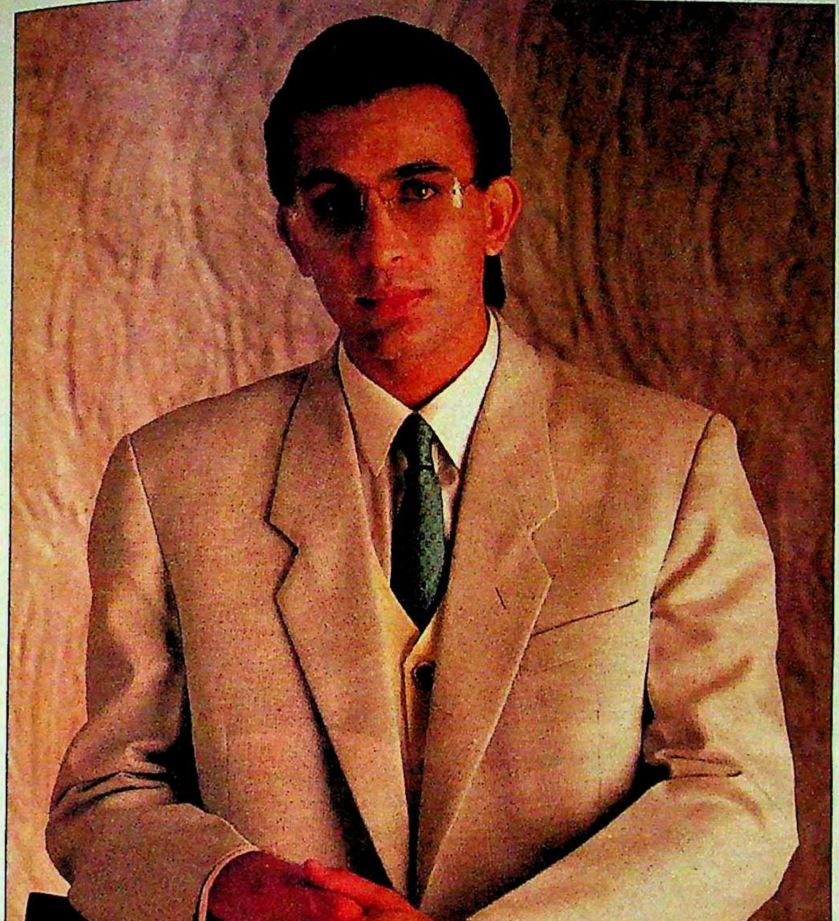

वूल और सिंथेटिक यार्न के बेहतरीन ब्लेण्ड्स की कताई का सबसे बढ़िया तरीका है वर्स्टेड स्पिनिंग सिस्टम.

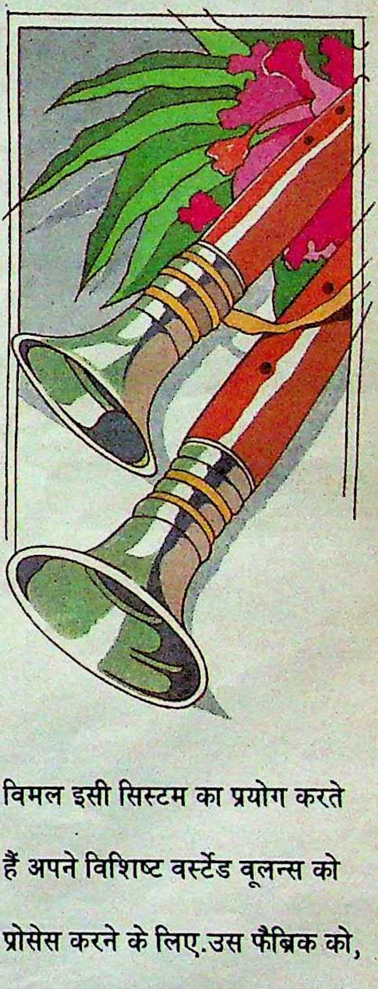

विमल इसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं अपने विशिष्ट वर्स्टेड वूलन्स को प्रोसेस करने के लिए.उस फैब्रिक को, जो रचना और रूपरेखा में इतना समृद्ध है कि इसे पहनने के लिए आप किसी ख़ास मौके का इंतज़ार करना चाहेंगे.

VIMAL®

WORSTED WOOLLEN
& POLYRICH SUITINGS

वर्स्टेड वूलन एवं पॉलिरिच सूटिंग्स

Mudra:A:RIL:4898 Hin.

अब शत्रुघ्न सिन्हा का जन-अभियान

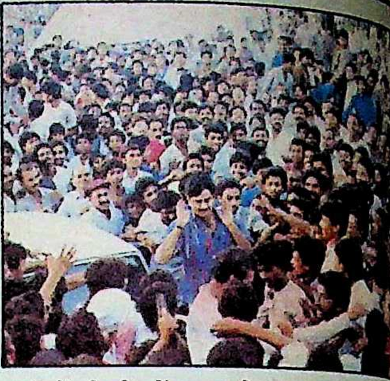

प्रशंसकों की भीड़ में शत्रुघ्न सिन्हा

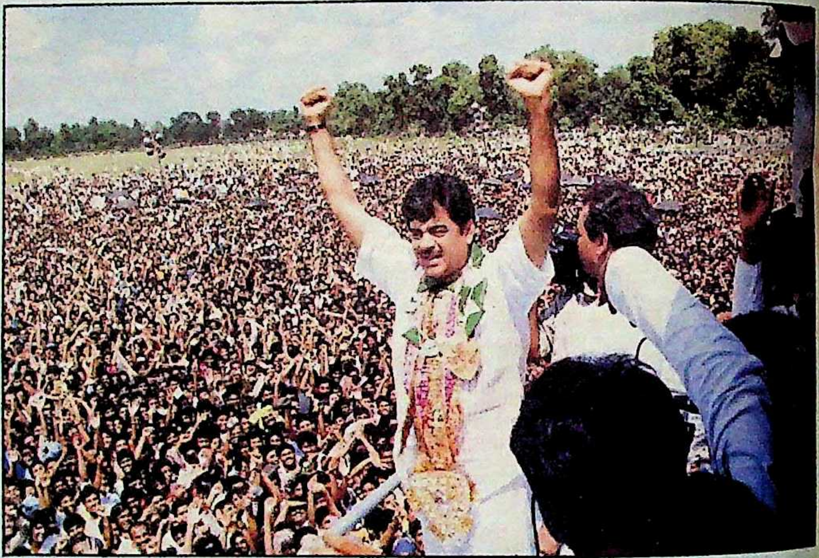

लोकप्रियता फिल्मी या राजनीतिक ? : शत्रुघ्न सिन्हा की एक जनसभा में उमड़ी भीड़

फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की मां श्यामा देवी सिन्हा को भी उसी बात की आशंका है जो आशंका आज से पांच साल पहले सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को हुई थी। अमिताभ जब राजनीति के परदे पर उतरने को उत्सुक होते दिखायी दिये थे, तो हरिवंश राय बच्चन ने उनसे कहा था कि फिल्मों में तुम पहले नंबर पर हो, पर राजनीति में तुम्हें आखिरी पंक्ति में भी कोई जगह मिलेगी, इसमें मुझे संदेह है। अमिताभ के राजनीतिक कैरियर को लेकर बच्चनजी की वह आशंका बिलकुल सच निकली। पटना के कदमकुआं मुहल्ले में स्थित अपने मकान में रह रहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की मां श्यामा देवी सिन्हा 'माया' से कहती हैं, "मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शत्रुघ्न बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। पर जहां तक राजनीति में उसके आने की बात है, कम-से-कम मैं तो उसे ऐसी गलती करने की सलाह नहीं दूंगी। वह चुनाव लड़े, यह भी मेरी दृष्टि में उसके हित में नहीं होगा। उसका लक्ष्य बगैर चुनाव लड़े ही अगर पूरा हो जाता है, तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत ? आज राजनीति भले लोगों के लिए नहीं है।" पर सितंबर माह के मध्य में शत्रुघ्न सिन्हा ने १५ सितंबर से १८ सितंबर तक बिहार में तूफानी ढंग से कई जनसभाएं कीं, जिनके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चली आ रहीं, उन अटकलबाजियों को फिर से यह रफ्तार मिल गयी कि बंबइया फिल्मों के परदे से कूदकर बिहारी बाबू अब राजनीति के अखाड़े में उतरे बिना नहीं मानेंगे और इस बार चुनाव लड़कर ही दम लेंगे।

शत्रु की सभाएं: 'बिहार बचाओ अभियान' नामक मंच के जरिये शत्रुघ्न ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। शत्रु इस मंच के मुख्य संरक्षक हैं और मंच के अध्यक्ष हैं, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सुबोध कांत सहाय। शत्रु ने घोषणा की कि उनका यह मंच बिलकुल गैरराजनीतिक है। इस मंच के मोनोग्राम में जंजीरों से जकड़ा हुआ बिहार है और बिहार की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बहरहाल, १५ सितंबर को पटना से शत्रु का काफिला रवाना हुआ। पहला मुकाम था, हाजीपुर। हाजीपुर के कचहरी मैदान में शत्रु की आमसभा थी। शत्रु के सभास्थल पर पहुंचने के बहुत पहले से हजारों की तादाद में भीड़ प्रतीक्षारत थी। भीड़ में ज्यादातर किशोरवय के लड़के थे। जाहिर था, यह उत्साहित भीड़ किसी राजनीतिक मसीहा को नहीं, बल्कि अभिनेता शत्रुघ्न को देखने पहुंची हुई थी। शत्रुघ्न सभास्थल पर पहुंचे, तो बिलकुल अफरातफरी सी मच गयी। सबके-सब शत्रुघ्न को निकट से देखने के लिए बेचैन थे। अपने संक्षिप्त भाषण में शत्रुघ्न ने बिहार की तबाही का हवाला देते हुए नौजवानों का आह्वान किया कि बिहार को बचाने और बनाने के लिए वे आगे आयें। इस अपार भीड़ को देख शत्रुघ्न अत्यंत उल्लसित थे, क्योंकि स्वयं उन्हें भी यह अनुमान नहीं था कि उनकी सभा में इतनी भीड़ जुटेगी। यों, राजनीति में शत्रुघ्न के प्रवेश की चर्चा रह-रह कर पिछले कई वर्षों से जोर मारती रही, पर शत्रुघ्न किसी जननेता का बाना धारणकर कभी जनसभा करने नहीं निकले थे। बिहार में पहली बार शत्रुघ्न बिहार की दुरावस्था के सवाल को लेकर इस तरह के सघन जन अभियान पर निकले थे। लोगों ने उन्हें हाथो-हाथ लिया भी। पर उस अपार भीड़ को जो शत्रुघ्न के लिए जुटी थी, उसे शत्रुघ्न अपने इशारे से चुनावी बूथ तक पहुंचा देंगे, ऐसी उम्मीद शत्रुघ्न को भी नहीं पालनी चाहिए।

१५ सितंबर को ही हाजीपुर से चलकर शत्रुघ्न मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस क्रीड़ास्थल में शत्रुघ्न की सभा निर्धारित थी। यहां भी वही जन-सैलाब था। मुजफ्फरपुर की सभा में शत्रुघ्न ने कहा कि देश में अब परिवर्तन की आवश्यकता है और यह परिवर्तन जनता दल के माध्यम से ही आ सकता है। उन्होंने कहा कि जो बिहार प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, आज वही भिखारी की स्थिति में पहुंचा हुआ है। मुजफ्फरपुर की सभा में भी शत्रुघ्न थोड़ी ही देर बोले। सभा के दौरान 'बिहारी बाबू जिंदाबाद' के नारे रह-रह कर गूंजते रहे। मुजफ्फरपुर की सभा के समापन के बाद रात्रि-विश्राम शत्रुघ्न ने मुजफ्फरपुर के ही निकट कांठी में किया। १६ सितंबर को 'बिहार बचाओ अभियान' का कारवां पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी पहुंचा। मोतिहारी के गांधी मैदान में

युवकों के अतिरिक्त बुजुर्गवार भी काफी संख्या में जुटे थे। शत्रुघ्न ने यहां कहा कि जो बिहार विकास के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पर हुआ करता था, आज वह २३वें नंबर पर आ गया है। बिहार को अवनति के ढलान से अब लुढ़कने नहीं दिया जायेगा। शत्रुघ्न ने गंडक, बागमती आदि सिंचाई परियोजनाओं की दुर्दशा का जिक्र किया और कहा कि इस सूबे के लोग पानी और बिजली जैसी जरूरी आवश्यकताओं के लिए तड़प रहे हैं। मोतिहारी की सभा खतम करने के तुरंत बाद शत्रुघ्न पश्चिम चंपारण के मुख्यालय बेतिया पहुंचे।

पिछली तीन सभाओं की भांति बेतिया में भी शत्रुघ्न को अपेक्षित भीड़ सुलभ हुई। पर बेतिया में 'मारवाड़ी युवा मंच' की ओर से विरोध-पत्र बांटा गया। दरअसल, फिल्मी पत्रिका 'स्टारडस्ट' के जून अंक में एक साक्षात्कार के क्रम में शत्रुघ्न की यह टिप्पणी छपी थी, "मैं कोई ठेठ बनिया स्वभाववाला मारवाड़ी या व्यवसायी नहीं हूं। ये मारवाड़ी-व्यवसायी हर सत्ताधारी दल को सलाम करते हैं। ये सही मायने में भारतीय नहीं हैं।" शत्रुघ्न के इस साक्षात्कार को लेकर पूरे देश के मारवाड़ी समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछेक जगह मुकदमे भी दायर किये गये। बेतिया मारवाड़ी युवा मंच उसी मुद्दे को लेकर आंदोलित था।

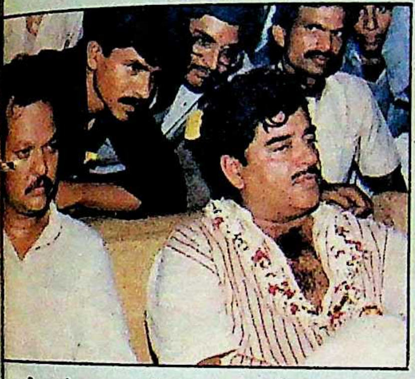

विपक्ष के साथ: सुबोधकांत सहाय के साथ शत्रुघ्न

शत्रु के इरादे: १८ सितंबर की दोपहर पटना के 'विद्यापति भवन' में 'बिहार बचाओ अभियान' मंच का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन था। इस सम्मेलन का उद्घाटनकर उसी दिन बिहारी बाबू बंबई के लिए कूच कर गये। पर साथ ही यह ऐलान भी करते गये कि उनका यह जनजागरण अब जारी रहेगा। यों, शत्रुघ्न ने लगातार इस बात का खंडन किया कि वे राजनीति में आ रहे हैं या कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर शत्रु के शुभेच्छुओं को अभी भी उम्मीद है कि ऐन मौके पर तमाम संशयों को झाड़कर शत्रु पटना संसदीय क्षेत्र से चुनावी दंगल में कूद पड़ेंगे। शत्रु के इस जन अभियान के आलोचकों का कहना है कि शत्रु को राजनीति के प्रति वैसी ही ललक है, जैसे किसी बच्चे में आग की लौ छूने की ललक होती है। बच्चा आग को छूना भी चाहता है, पर आग से डरता भी है। पर शत्रु बेहद सयाने हैं। वे जानते हैं कि अपनी फिल्मी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर ही राजनीति का सुर अलापने में उन्हें लाभ है। राजनीति में सीधे घुसकर वे झुलस जायेंगे और कमोबेश अमिताभ की सीं गति में पहुंच जायेंगे जो अब लाख जोर लगाकर भी 'जादूगर' जैसी फिल्मों के जरिये अपना जादू नहीं दिखा पा रहे हैं। शत्रु का 'क्रेज' अमिताभ सरीखा भी कभी नहीं रहा। वे एक औसत से कुछ अधिक स्तर के अभिनेता रहे हैं। इसलिए राजनीति में आकर अगर वे पिट गये, तो वापस 'बाक्स आफिस' पर फिर से पांव जमाना उनके लिए असंभव ही हो जायेगा। इसलिए राजनीति व फिल्म के संधि-स्थल पर खड़े रहने का जो लाभ शत्रु को मिल सकता है, वह राजनीति में पूरी तरह शामिल होकर नहीं। बिहार के सवाल पर मुखर होने से उनकी एक 'प्रोग्रेसिव इमेज' (प्रगतिशील छवि) भी बन रही है। पर एक तरफ वे खुद कहते हैं कि वे एक तटस्थ व्यक्ति की भूमिका में रहकर सबके अच्छे-बुरे पर समीचीन टिप्पणी करेंगे, वहीं उनका यह कहना कि वे जनता दल के चुनाव अभियान की कमान संभालेंगे, शत्रु को बेशक अनर्गल विवाद के फंदे में डालेगा। एक तटस्थ बिहारी-प्रवक्ता के रूप में जो प्रतिष्ठा शत्रु को मिल सकती है, वह प्रतिष्ठा जनता दल के खूंटे से बंधकर बोलने पर उन्हें नहीं मिल सकेगी। शत्रु को इस बात का मुगालता भी नहीं होना चाहिए कि उनके 'फैन' उनके कहे पर किसी दल-विशेष को जाकर वोट डाल आयेंगे। राजेश खन्ना भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का चुनाव अभियान करने गये थे। पर राजेश कांग्रेस के वास्ते कितने वोटों की वृद्धि करवा सके? और फिर शत्रु कभी राजेश खन्ना की ऊंचाई के अभिनेता भी नहीं रहे हैं। फिल्मों में अपनी गिरती कीमत को उठाने के लिए यों भी शत्रु परेशान हैं। वे किसी-न-किसी बहाने सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, ताकि फिल्मों में उनका बाजार भाव बना रहे। पाकिस्तान के मरहूम राष्ट्रपति जनरल जियाउलहक से अपनी दोस्ती को भी शत्रु ने कुछ ही समय पहले खूब उछाला था। राजनीति में आने की बात भी शत्रु इसी तरह चटखारे लेकर गुजरे वर्षों में उछालते रहे हैं। शत्रु अगर मात्र चर्चित बने रहने के लिए राजनीतिक स्टंट का सहारा ले रहे हैं, तो वह भी क्षम्य है, क्योंकि सिने जगत में डूबता अभिनेता हर नयी हीरोइन के संग अपने रोमांस के झूठे किस्से उड़वाता है और शत्रु अगर राजनीति के संग ही अपने रोमांस की कथा गढ़वा रहे हैं, तो यह आपत्तिजनक नहीं। शत्रु अगर सही मायने में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए पूरे मन से सामने आना होगा। महज बयानबाजी व भाषण देने से बिहार न तो बचेगा, न बनेगा और न जगेगा। **—विकास कुमार झा**

—छाया: दीपक कुमार

साक्षात्कार: शत्रुघ्न सिन्हा

'मैं लल्लू प्रसाद मंत्री नहीं बनना चाहता'

फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सक्रिय राजनीति में आयेंगे या नहीं, यह एक ऐसी पहेली है, जिसका जवाब शायद खुद शत्रुघ्न सिन्हा को भी मालूम नहीं। पिछले कई वर्षों से शत्रुघ्न के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म होती रही है, पर अब तक शत्रुघ्न ने किसी भी राजनीतिक दल से विधिवत अपना नाता नहीं जोड़ा है। अब जबकि संसदीय चुनाव के चंद महीने शेष रह गये हैं, तो स्वाभाविक रूप से शत्रुघ्न को लेकर अटकलें फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। सितंबर के मध्य में शत्रुघ्न ने 'बिहार बचाओ' नामक अपने अभियान के तहत बिहार में कई जगह सभाएं कीं, तो इन अटकलों को पंख ही लग गये। प्रस्तुत हैं, 'माया' से शत्रुघ्न की बातचीत के मुख्य अंश:

माया: ***आपकी जनसभाओं में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। क्या यह भीड़ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को देखने-सुनने पहुंची थी या बिहार में बेहतर बदलाव लाने का इरादा रखनेवाले एक व्यक्ति की बातों को सुनने पहुंची थी?***

सिन्हा: *बेशक अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को चाहनेवाले तो सभा में आये ही थे। करिश्मा तो नेता और अभिनेता दोनों के लिए अनिवार्य है। पर अगर सिर्फ अभिनेता शत्रुघ्न को ही सुनने के लिए लोग आये होते, तो मुझसे मेरी फिल्मों के कुछ डायलाग सुनाने की फरमाइश जरूर करते। पर ऐसा अनुरोध कहीं भी सभाओं के दौरान लोगों ने नहीं किया। इसलिए मुझे तो लगता है कि मेरी सभाओं में वे लोग आये थे, जो बिहार में एक जरूरी और बेहतर बदलाव का जज्बा दिल में रखते हैं। बिहार के लोग राजनेताओं से बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। नेताओं के नाम से हर आम बिहारी नफरत करने लगा है, क्योंकि नेताओं ने कदम-कदम पर बिहार को गिरवी रखा है। मेरे प्रति बिहारवासियों ने जो स्नेह और विश्वास जताया है, सच पूछिये, तो इससे मैं*

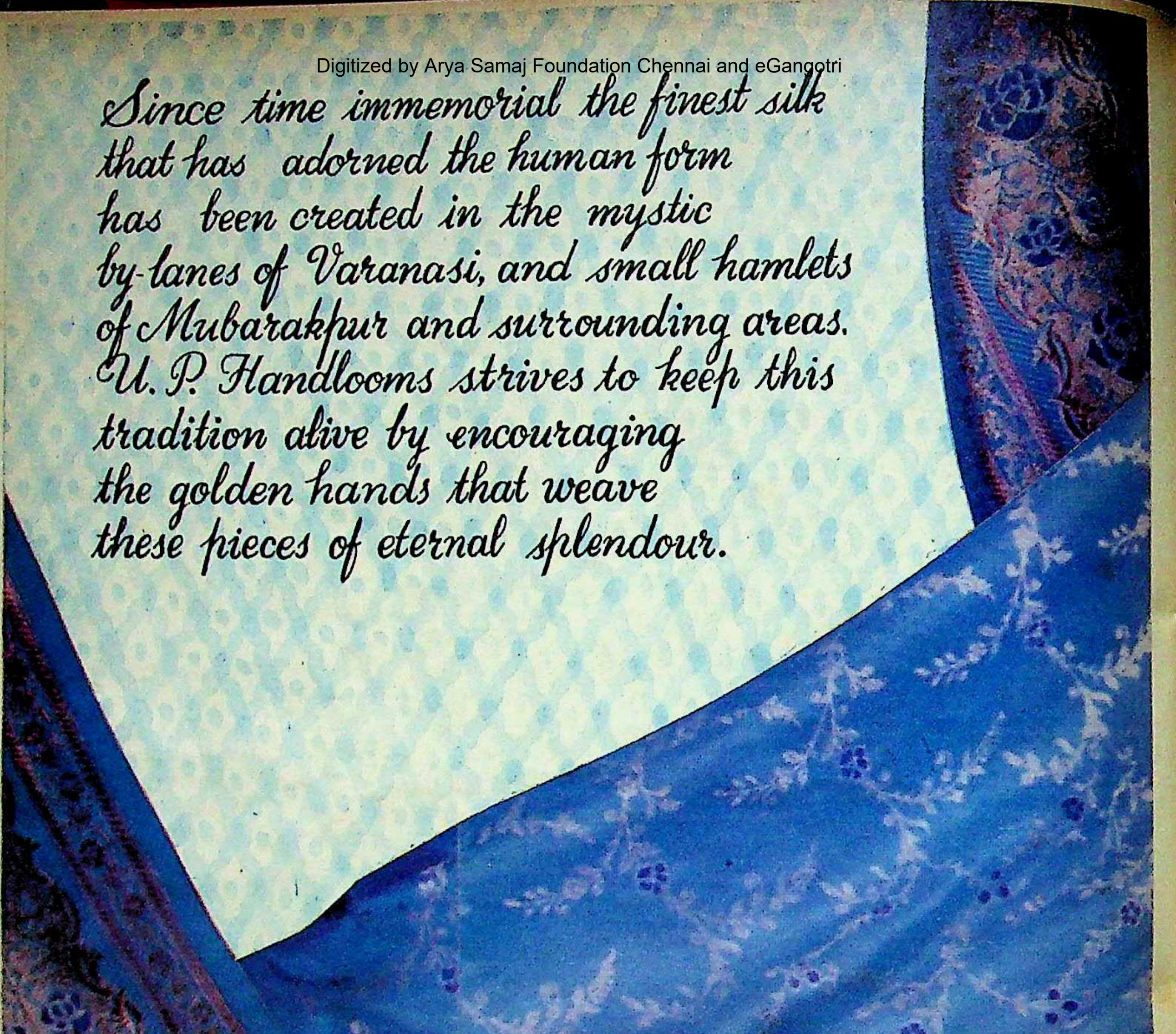

*Since time immemorial the finest silk
that has adorned the human form
has been created in the mystic
by-lanes of Varanasi, and small hamlets
of Mubarakpur and surrounding areas.
U. P. Handlooms strives to keep this
tradition alive by encouraging
the golden hands that weave
these pieces of eternal splendour.*

U.P. HANDLOOMS

- PLAIN AND PRINTED BANARASI SAREES.
- SILKEN DRESS MATERIAL.
- TANCHUI SAREES.

WE SOLICIT YOUR PATRONAGE AT OUR FOLLOWING SHOWROOMS :-

- NEW DELHI - Aurbindo Place, Hauz Khas, Khan Market • AGRA - Sanjay Place. • LUCKNOW - Mayfair Building.
- KANPUR - P. P. N. Market. • ALLAHABAD - Civil Lines, • VARANASI - Nichi Bagh • JAIPUR - M. I. Road.
- CHANDIGARH - Sector 17-C. • BHOPAL - T. T. Nagar.

AND 150 OTHER SHOWROOMS SPREAD ALL OVER THE COUNTRY.

KRISHNA/U.P.H/Col.-1

U.P. STATE HANDLOOM CORPORATION LTD.
(A Govt. of U. P. Undertaking)
Hathkargha Bhawan, G. T. Road, Kanpur (U. P.)

CC-0

भयभीत भी हूं कि पता नहीं कितनी दूर तक मैं इस जन-विश्वास को लेकर चल सकूंगा, क्योंकि मेरे योगदान की भी एक सीमा है। मैं अभियान की शुरुआत कर सकता हूं और उसे गति दे सकता हूं, पर चौबीस घंटे पूरे तौर पर मैं ही सब कुछ थामे रहूं, यह व्यावहारिक रूप में संभव नहीं। मैं आज तक किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हुआ हूं। बिहार में जरूरी बदलाव के लिए चलाये गये अभियान में मेरी भूमिका एक उत्प्रेरक की ही हो सकती है जो अभियान की सार्थक उपलब्धि के बाद फिर वापस बाहर निकल आये। शत्रुघ्न सिन्हा किसी राजनीतिक दल के वास्ते भीड़ या मजमा लगाने की सामग्री नहीं बन सकता। हमारी बस एक ही मुराद है कि चाहे जिस किसी दल या व्यक्ति से हो, पर बिहार को तबाही के गर्त से निकाले। बिहार के अच्छे दिन वापस आयें। मुझे राजनीति नहीं करनी। मैं एमएलए, एमपी या मंत्री नहीं बनना चाहता। मैं किसी मंत्रालय में लल्लू प्रसाद मंत्री की तरह कुरसी से चिपककर ऊंघता रहूं, यह मुझे गवारा नहीं। मैं जहां हूं, जो भी हूं, बस ठीक हूं। लोगों ने जो स्नेह मेरे वर्तमान रूप को दिया है, उसमें मेरे राजनीति में आ जाने से कोई वृद्धि नहीं हो जायेगी। हां, एक जागरूक बिहारी की भूमिका तो मैं आजीवन निभाना चाहूंगा जो बिहार के सवाल को लेकर सत्ता या विपक्ष के हर सही-गलत कदम पर बिना किसी लाग-लपेट के बोले। मेरी इस भूमिका से बिहार के राजनीतिक महंतों को पता नहीं, क्यों परेशानी महसूस हो रही है।

माया : आप कहते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में आने के बजाय बिहार में बदलाव के लिए बस एक उत्प्रेरक की भूमिका अपनायेंगे। ऐसे में बिहार की परिवर्तनकामी जनता जो आपकी समक्ष से आपके प्रति आस्था रखती है, वह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी?

सिन्हा : इसीलिए मैंने अपने अभियान के तहत बिहार के प्रति समर्पण का भाव रखनेवाले लोगों का आह्वान किया है कि वे आयें और एकजुट होकर बदलाव की इस मुहिम का नेतृत्व संभालें। चाहे वह कांग्रेस से जुड़े लोग हों या विपक्ष से संबद्ध, मैंने इस संघर्ष के लिए सबको न्यौता दिया है। कांग्रेस के लोगों में यह बात धंस गयी है कि मैं कांग्रेस का कट्टर दुश्मन हूं, जबकि सचाई यह है कि कांग्रेस में मेरे कई अच्छे दोस्त हैं। मुझ पर आरोप लगता रहा है कि मैं सिर्फ विपक्ष के मंच से ही बोलता हूं। दरअसल, अपनी बात रखने के लिए हर किसी को एक मंच की आवश्यकता होती है। कोई कहे कि कांग्रेस के किसी मंच पर मुझे कभी आमंत्रित किया गया हो और मैं न गया होऊं, हां, इतना जरूर है कि कांग्रेस की तुलना में मुझे विपक्ष का रास्ता ज्यादा ठीक लगता है कि ऐसा नहीं कि विपक्ष ने मुझ पर कोई अहसान किया है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। सच तो यह है कि मेरे हर आड़े वक्त में विपक्ष बिलकुल खामोश बैठा रहा। कुछ साल पूर्व जब मैं पटना में एक अस्पताल निर्माण के लिए 'चैरिटी-शो' करना चाह रहा था और ऐन आखिरी वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने उस कार्यक्रम को लेकर अपनी असहमति जाहिर कर दी थी, तो उस समय मुझे एक भी विपक्ष का नेता नहीं दिखा जो दुबे की इस कार्रवाई की भर्त्सना करने सामने आया हो। देशरत्न डा० राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का जब मैंने अनावरण किया था, उस समय भी कुछ लोगों ने बड़ा बावेला मचाया था, पर उस मौके पर भी कोई विपक्ष का नेता मेरे लिए एक शब्द भी बोलने की उदारता नहीं दिखा सका था। इसी तरह ताशकंद के फिल्म समारोह में मेरी फिल्म जाने से रोक दी गयी थी, उस समय भी किसी विपक्षी नेता ने विरोध प्रकट नहीं किया था। कुल मिलाकर स्थिति यही रही कि जिन पर नाज था, वही पत्ते हवा देने लगे। ठीक है, व्यक्तिगत शत्रुघ्न के लिए विपक्ष के नेता भले उदासीन रहे हों, पर मुझे लगता है कि इस देश के लिए आनेवाले दिनों में विपक्ष के ही नेता शायद कुछ कर सकें। मैं स्पष्ट कर दूं कि सत्ता में आने पर अगर विपक्ष के नेताओं द्वारा जनाकांक्षाओं की उपेक्षा की गयी, तो उन लोगों की भी मैं सख्ती से आलोचना करूंगा। मैं बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हूं। तटस्थ होकर समालोचना करूंगा। मैंने 'बिहार-बचाओ' का अभियान शुरू किया है और इसके संग-संग मेरा अभियान 'बिहार बनाओ' का भी है। जो दल इसमें असहयोग करेगा, उससे हम ठीक से निपटेंगे।

मेरी पत्नी अगर कभी मुझे तलाक देगी, तो समझ लीजियेगा कि बिहार के कारण ही यह दुर्घटना हुई, क्योंकि मेरी पत्नी को यह बात खलती रहती है कि मैं अपनी फिल्मों के सारे कामकाज छोड़ बार-बार क्यों बिहार भागता रहता हूं।

माया : क्या इस बार आप चुनाव-बहिष्कार का आह्वान करने की नहीं सोच रहे हैं?

सिन्हा : चुनाव-बहिष्कार का आह्वान मैंने पिछली बार किया था। बाद में मैंने महसूस किया कि वह मेरी गलती थी। विरोध, बहिष्कार करके नहीं, बल्कि लड़कर किया जाना चाहिए। बहिष्कार तो मैदान छोड़कर भाग जाना हुआ। मैं विपक्ष को समर्थन देने के लिए लोगों से कहूंगा और बाकायदा विपक्ष के लिए इस बार चुनाव अभियान भी चलाऊंगा।

माया : क्या आप स्वयं भी चुनावी-जंग में उतरेंगे?

सिन्हा : (ठहाका) इसकी संभावना बहुत कम है। अभी से क्या कहा जा सकता है?

माया : आपकी इन गतिविधियों से आपके फिल्मी कैरियर पर कैसा असर पड़ रहा है?

सिन्हा : समय काफी लगता है, इन गतिविधियों में। अपनी फिल्मों की शूटिंग छोड़कर मैं बिहार आता हूं। बिहार मुझे बार-बार खींचता है। बंबई में रहकर भी मेरा मन हरदम बिहार में ही विचरता रहता है। एक दिलचस्प बात बता दूं, अभी से आपको कि मेरी पत्नी अगर कभी मुझे तलाक देगी, तो समझ लीजियेगा कि बिहार के कारण ही यह दुर्घटना हुई, क्योंकि मेरी पत्नी को यह बात खलती रहती है कि मैं अपनी फिल्मों के सारे कामकाज छोड़ बार-बार क्यों बिहार भागता रहता हूं। पिछले दस-पंद्रह वर्षों से बिहार के सवालों पर मैं तत्पर रहा हूं। १९७९ में पिताजी के निधन के बाद तो लगातार पटना आने की अनिवार्यता सी हो गयी, क्योंकि मेरी मां पटना में ही रहती हैं। वैसे भी, मैं अपनी फिल्मों की शूटिंग ज्यादातर बिहार में रखने की कोशिश करता हूं, ताकि बिहार में अपने लोगों के बीच रहने का सुख मिल सके।

माया : फिल्मी दुनिया में सदैव सुर्खियों में बने रहने के लिए अधिसंख्य अभिनेता आये दिन अभिनेत्रियों से अपने रोमांस के झूठे किस्से उड़वाते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी राय है कि अब इस उम्र में किसी हीरोइन से आपके रोमांस का किस्सा नहीं उड़ पा रहा है, इसलिए आप पिछले कुछ सालों से 'राजनीतिक रोमांस' के ही किस्से उड़वाकर सुर्खी में बने रहना चाहते हैं?

सिन्हा : अब रोमांस की बात पर मुझे ज्यादा न छेड़िये। जहां तक अभिनेत्रियों से रोमांस की बात है, तो आज भी इस बात के लिए कई-कई रात मेरी पत्नी की नींद हराम रहती है। मैं बार-बार बिहार आता हूं, तो पत्नी को यह डर बना रहता है कि शत्रु का वहां कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है।

—विकास कुमार झा

छाया : दीपक कुमार

हल्द्वानी कांड

पुलिस बर्बरता की नयी मिसाल

महिला एकता
जिन्दाबाद

एनडी तेरे गांव में...हल्द्वानी में महिलाओं का प्रदर्शन

न्यायमूर्ति आनंदनारायण मुल्ला ने बगैर पर्याप्त आधार के ही पुलिस को 'गुंडों का सबसे संगठित गिरोह' करार नहीं दिया था। समाज के कमजोर और सीधे-सादे लोगों से पुलिसिया सलूक के सैकड़ों नमूनों का जायजा लेने के बाद न्यायाधीश ने यह नतीजा निकाला था। मनोरमता और शांति के लिए विख्यात कुमाऊं के तराई क्षेत्र में स्थित हल्द्वानी कस्बे में ५ सितंबर की रात से १२ सितंबर तक चलती रही पुलिस बर्बरता ऐसे ही नमूनों की एक मिसाल है। हल्द्वानी में पहले तो पुलिसकर्मियों ने एक विवाहित युवती से बलात्कार किया और उसके पिता-पति की पिटाई की, फिर जब जनता ने इसका विरोध किया तब हजारों की भीड़ पर गोलीबारी कर ८-९ लोगों की हत्या कर दी तथा सौ से अधिक को घायल किया, और जब इससे भी जी नहीं भरा, तो जबरन कर्फ्यू लगवाकर अगले चार-पांच दिनों तक बहशियाना हरकतें करती रही। इससे जनरोष की जो आग भड़की, वह कुमाऊं मंडल के तीनों जिलों-नैनीताल, अलमोड़ा और पिथौरागढ़—में देखते-देखते फैल गयी। तराई, भाभर और पर्वतीय अंचलों में पुलिस चौकियों पर क्रुद्ध जनता ने हमले किये और पूरा पर्वतीय अंचल कई दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। यह सब तब हुआ जब हल्द्वानी में जिलाधिकारी पीडी सुधाकर और एसएसपी कविराज नेगी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, जबकि आयुक्त ओएन वैद्य तथा अन्य अधिकारी सूचना पाने के दस घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी, जिनके गांव और चुनाव दोनों का क्षेत्र यही है, घटना के एक पखवारे बाद तक हल्द्वानी जाने का साहस नहीं बटोर पाये।

अबला की लाज: इस हंगामे की जड़ नेपाली मूल की २० वर्षीया विवाहित युवती कमला बतायी जाती है। वह हल्द्वानी से ७० किलोमीटर दूर मनाधेर गांव में रहती थी। मनाधेर से पहाड़ पानी क्षेत्र तक नेपाली मूल के काफी लोग ठेके पर आलू की खेती करते हैं। यह क्षेत्र मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के गांव पद्मपुरी से थोड़ा ही ऊपर पड़ता है। कमला ५ सितंबर की शाम अपने पति रूपसिंह, ससुर तथा जेठ के साथ आलू बेचने नवीन मंडी (हल्द्वानी) आयी थी। मंडी में खेमानंद उर्वादत्त तिवारी फार्म के मालिक मोहनचंद्र तिवारी के अनुसार, "कमला अपने पति तथा रिश्तेदारों के साथ रात में मेरी फर्म पर रुकी थी। सुबह मंडी आने पर मुझे पता चला कि कमला के साथ मंडी चौकी की पुलिस ने बदसलूकी की है।"

इसके बाद मंडी के सभी दुकानदार और मजदूर एकत्र हो गये। वे मंडी चौकी गये, तो पुलिस ने उन्हें डपट कर भगा दिया। इसकी सूचना पाकर हल्द्वानी थाने के प्रभारी निरीक्षक रामचरण सिह मंडी पहुंच गये। वे कमला को लेकर पुलिस चौकी गये। कमला ने अपने साथ दुर्व्यवहार करनेवाले दीवान गीतम सिह और दो सिपाहियों महेंद्र सिंह व हरीश चंद्र को पहचान लिया। उन तीनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। रूपसिंह ने व्यापारियों तथा पुलिस को बताया कि बीती रात वह अपनी पत्नी कमला, बड़े भाई तथा पिता के साथ खेमानंद उर्वादत्त फर्म की छत पर सोया था। रात लगभग ११ बजे तीन पुलिसकर्मी नशे में धुत हो छत पर आ गये। पुलिसवालों ने उसे पीटा और भाई व पिता सहित नीचे ले आये। फिर गीतम सिंह कमला के साथ अकेला छत पर रह गया। फर्म के पल्लेदार भी यही बात कह रहे थे।

बहरहाल, सुबह भीड़ काफी एकत्र हो गयी थी। परगनाधिकारी जीडी नैनवाल भी वहां आ गये थे। जनता दोषी पुलिसकर्मियों को पैदल हल्द्वानी थाने तक ले जाने की मांग करने लगी। परगनाधिकारी नैनवाल का कहना था कि अभियुक्तों को उनकी कार से ले जाया जाये। पर पुलिस निरीक्षक रामचरण सिह इस बात पर अड़ गये कि वे अभियुक्तों को पैदल ही थाने तक ले जायेंगे। मंडी से हल्द्वानी थाने की दूरी तीन किलोमीटर से अधिक है। कमला के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार की घटना की खबर फैलती गयी और अभियुक्तों को पैदल ले जा रही पुलिस के पीछे भीड़ एकत्र होती गयी। मंगल पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचने तक भीड़ ने पथराव कर दिया। रामचरण सिह को भी पत्थर लगा। इस पर भी पुलिस, थाने तक अभियुक्तों को पैदल ले गयी। पीछे-पीछे भीड़ भी थाने जा पहुंची। व्यापार मंडल के लोग इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।

फायरिंग का राज: भीड़ ने थाने को घेर लिया और मांग करने लगी कि अपराधी पुलिसजनों को निलंबित और जनता के हवाले किया जाये। थाने पर कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएस फुलौरिया रक्षामंत्री केसी पंत की सुरक्षा में बाजपुर थे। पंत अपने पांच दिवसीय दौरे पर वहां आये थे। फुलौरिया खबर पाते ही हल्द्वानी आ गये। भीड़ एक मोटर साइकिल फूंक चुकी थी। थाने पहुंच कर फुलौरिया ने जनता के कुछ लोगों से विचार-विमर्श शुरू किया। बताया जाता है कि इसी दौरान जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष खजान पांडेय ने मामले को ऐसी हवा दी कि जनता भड़क उठी। थाने पर पथराव बहुत तेज हो गया। पुलिस के पास न लाठियां थीं और न ही आंसू गैस। अचानक थाने से पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर गोली मारी गयी। हालांकि जिलाधिकारी पीडी सुधाकर का कहना है कि फायरिंग के आदेश परगनाधिकारी ने दिये थे, पर एक हफ्ते बाद तक यह विवाद का विषय बना हुआ था कि गोलियां किसके आदेश पर चलायी गयीं? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रूरता पर उतर आयी पुलिस ने गोली चलाने का आदेश जबरन लिया।

यदि थाने पर पथराव कर रही भीड़ को ही तितर-बितर करना था, तो बस स्टैंड, स्टेट बैंक, ओके होटल जाकर पुलिस ने गोलियां क्यों बरसायीं? इस प्रश्न का उत्तर न जिला प्रशासन के पास है, न ही पुलिस अधिकारियों के पास। २४ वर्षीय पुष्कर सिह को उस समय गोली मारी गयी जब वह भूमि विकास बैंक से अपना ड्राफ्ट भुना

रहा था। पुष्कर की शादी इसी जून में हुई थी। उसके बाद उसकी विधवा पत्नी और उसके पागल भाई की देखभाल करनेवाला कोई नहीं रहा। २० वर्षीय उस्मान को गोली से घायल देख उसके मित्र अनवर ने उठाना चाहा। पुलिस ने अनवर को भी गोली मार दी। गिरीशचंद्र उपाध्याय ओके होटल की छत पर खड़ा यह मंजर देख रहा था कि एक गोली ने उसे भी पलटा दिया। इन चारों की मौत हो गयी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए चार आदमियों की दो दिन बाद मौत हो गयी। स्थानीय लोग पुलिस की गोली से एक और आदमी मारे जाने का दावा करते हुए बताते हैं कि कई लोग लापता हैं और यह पुलिस ही बता सकती है कि वे जिंदा हैं या नहीं। हल्द्वानी के तहसीलदार द्वारा जारी सूची के अनुसार, गंभीर रूप से घायलों की संख्या १३ तथा अन्य घायलों की संख्या ४५ है। किंतु स्थानीय लोगों के अनुसार फायरिंग और राइफल के बट से की गयी अंधाधुंध पिटाई से सौ से ज्यादा लोग घायल हुए जिनमें करीब दो दर्जन लोगों की हालत गंभीर थी। क्रूरता की दहशत ऐसी थी कि कई घायलों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर उनके सगे-संबंधी ले गये। दो घायलों—अनवर अली और शेखर—की मौत बरेली में हुई।

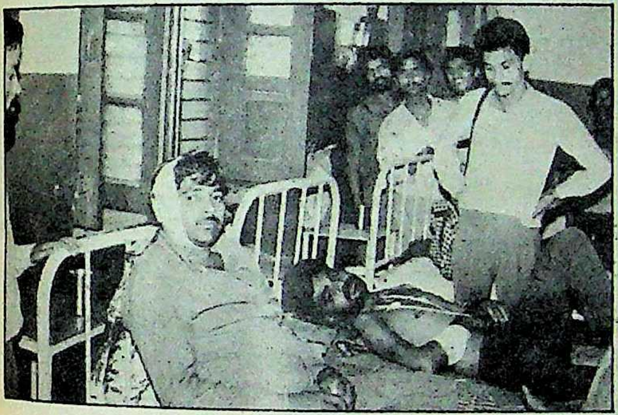

गोलीबारी के गवाह: पुलिस की गोली से घायल लोग अस्पताल में

जनरोष का सबब: पुलिसकर्मियों के अपराध और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानेवाले हल्द्वानीवासियों को सबक सिखाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगाया गया। फिर भी तीन-चार दिनों तक क्रुद्ध जनसमुदाय अपने जेहाद के मोर्चे पर डटा रहा। हल्द्वानी गोलीकांड की खबर से अलमोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ की जनता ने थानों का घेराव और आगजनी शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में पुलिस कार्यालय फूंक दिया गया। कलेक्ट्रेट पर पथराव हुआ। नैनीताल शहर में थाने पर पथराव हुआ। पुलिस की एक जीप जला दी गयी। फायरब्रिगेड की गाड़ी नाले में डाल दी गयी। भीमताल, रूद्रपुर, बाजपुर, किच्छा, रामनगर में भी हिंसक वारदातें हुईं। दिनेशपुर चौकी फूंक दी गयी। अलमोड़ा में बागेश्वर थाना जला दिया गया। रामनगर में पुलिस ने ६ घंटे तक फायरिंग भी की। यह सब होने के बावजूद नैनीताल के किसी भी जन प्रतिनिधि ने शांति स्थापित करने की पहल नहीं की। सांसद सत्येंद्रचंद्र गुड़िया और स्थानीय विधायक मोतीराम सांगुडी चार दिन बाद अस्पताल पहुंचे। हल्द्वानी थाने के पीछे रहनेवाले केएन जोशी के घर पर बने गोलियों के निशान गोलीकांड की हकीकत बयान करते हैं। केएन जोशी की प्रतिक्रिया थी, "जब मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के क्षेत्र में हम इतने अधिक असुरक्षित हैं, तो प्रदेश के अन्य स्थानों का हाल क्या होगा?"

कमला के साथ पुलिस दीवान की बदसलूकी के साथ ही जनरोष में उबाल आने के दो कारण बताये जाते हैं। पहला यह कि पुलिसवालों के व्यभिचार और अत्याचार इतने बढ़ गये हैं कि अब सहे नहीं जाते, और दूसरा यह कि पुलिसकर्मियों ने हल्द्वानी में अपनी तैनाती मानो हमेशा के लिए करा रखी है। हल्द्वानी के ही पीयूष डालकोटी का कहना है, "निहत्थी जनता पर गोली चलानेवाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहे।"

कुमाऊं के आयुक्त ओएन वैद्य पिछले पांच वर्षों से यहीं तैनात हैं। ऐसे दर्जनों कर्मचारी हैं, जो पांच से लेकर सत्रह वर्षों से हल्द्वानी में जमे हैं। धारी की ब्लाक प्रमुख श्रीमती शांति विष्ट की मांग है, "महिलाओं पर अत्याचार करनेवाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाये।" जनतादल के नेता लक्ष्मण सिंह क्वीरा की मांग है, "हल्द्वानी थाने के सभी पुलिसकर्मियों को पहले तो निलंबित किया जाये, फिर कोई जांच हो।" जब हल्द्वानी में पांच दिनों बाद कर्फ्यू में ढील दी गयी तब १२ सितंबर को हल्द्वानी महिला संगठन ने जुलूस निकाला। जुलूस में मुख्य नारा था "एनडी तेरे गांव में, नारी लगी है दांव पर!" जुलूस का नेतृत्व कर रही किरण पांडेय विजयलक्ष्मी, मंजू टंडन, उषा जैन का कहना था कि मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को यहां अवश्य आना चाहिए था।

पर मुख्यमंत्री तिवारी घटना के १७ दिन बाद २३ सितंबर को हल्द्वानी पहुंचे—२१ सितंबर को उत्तराखंड संघर्षवाहिनी, विपक्षी दलों, छात्र एवं महिला संगठनों द्वारा इस कांड के खिलाफ साझा प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने के बाद। तिवारी ने घटना में मरे प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, गंभीर रूप से घायलों को २५-२५ हजार और मामूली तौर पर घायलों को १५-१५ हजार रु० देने की घोषणा की। वे घटना में मरे पुष्कर सिंह के घर भी गये और उसका सरकारी ऋण माफ करने के साथ-साथ परिवार की दो विधवाओं को विधवा पेंशन देने की घोषणा की। इसके पूर्व लखनऊ में खबर दी गयी कि राज्य सरकार हल्द्वानी कांड की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त जज जेबी सिंह से करायेगी। फिर भी अभी पुलिस के प्रति आक्रोश थमा नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि घटना हुए एक पखवारा बीत जाने तक हल्द्वानी नहीं गया है, जबकि बरेली भाजपा के विधायक डा० दिनेश जौहरी, लखनऊ से जनतादल के नेता व पूर्व मंत्री मोहन सिंह तथा पिथौरागढ़ से उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक काशी सिंह ऐरी मृतकों के परिजनों और घायलों के बीच जाकर सहानुभूति जता आये हैं। १६ सितंबर को हल्द्वानी का दौरा कर उप्र जनतादल के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने वहां के दहशत और आक्रोश भरे हालात की चर्चा करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिला मैजिस्ट्रेट को तुरंत हटाने की मांग की। इससे कांग्रेस के प्रति जनता में रोष और भी बढ़ता जा रहा है।

सबसे आश्चर्यजनक पहलू तो यह है कि कमला और उसके पति रूपसिंह का कोई पता ठिकाना नहीं है। पुलिस का कहना है कि रूपसिंह ने अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखायी है, अतः कमला की डाक्टरी जांच नहीं करायी गयी। मुलायम सिंह का आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस ने दोनों को छिपा रखा है ताकि ५-६ सितंबर के कुकर्मों और अवांछनीय गोलीबारी के सबूत मिटाये जा सकें और उनसे मनचाहे बयान लिए जा सकें। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि पुलिस ने रूपसिंह से मनचाही रिपोर्ट लिखवाकर दोनों को दफा कर दिया है। नैनीताल के जिलाधिकारी पीडी सुधाकर ने 'माया' को बताया, "कमला नेपाल चली गयी है। उससे संपर्क कर उसके बयान लेने की कोशिश जारी है। दोषी पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक जांच के बाद उचित दंड दिया जायेगा। यदि कमला कहती है, तो उन पर बलात्कार का मुकदमा भी कायम किया जायेगा।" लेकिन जब पीड़ित पति-पत्नी को डंडे के जोर पर पुलिस अपने माफिक बना लेगी, तब क्या होगा?

—निशीथ जोशी, हल्द्वानी से लौटकर

ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेन्ट केक
ज़बरदस्त झाग ! किफ़ायती धुलाई !
किफ़ायती धुलाई

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा

डिटर्जेन्ट केक

A *Kusum* Product

विश्वास के साथ खरीदिये

Contract KP. 96.86 HIN

दिल्ली विश्वविद्यालय

क्या शिक्षक आंदोलन का स्वरूप बदलेगा?

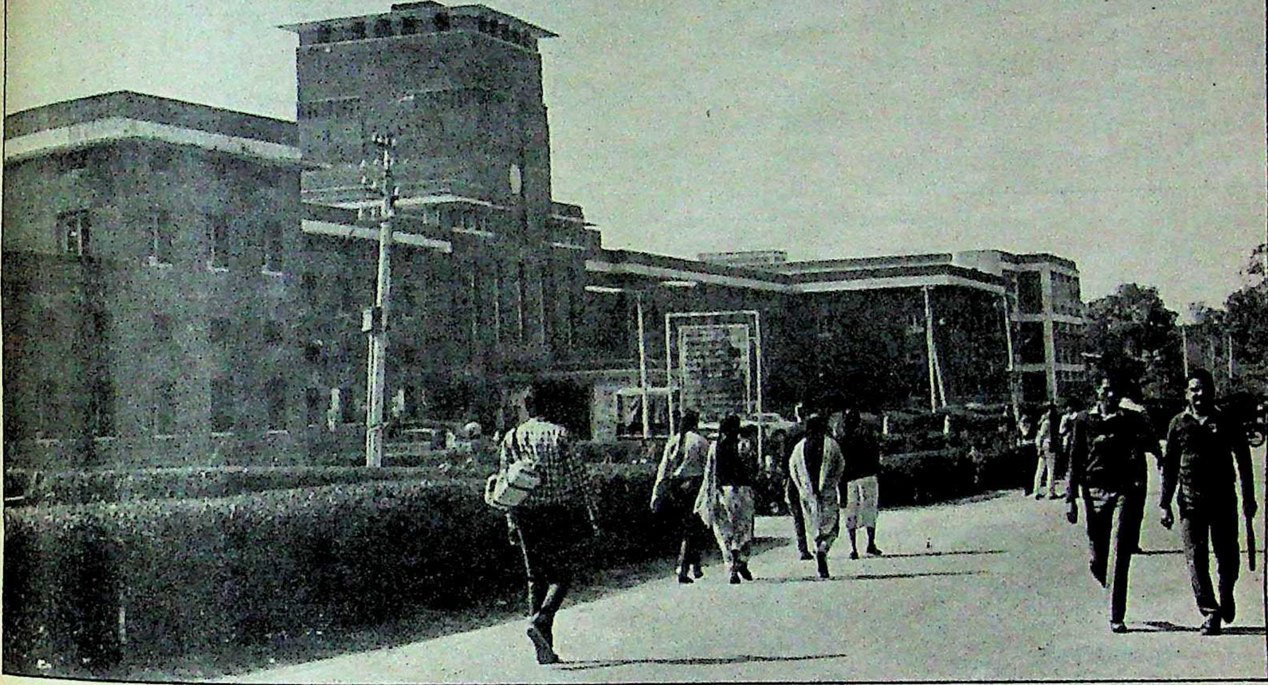

शिक्षक दिवस हर वर्ष की तरह आया और निहायत औपचारिक माहौल में इसे ३६५ दिनों के लिए फिर विदा कर दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी कुछ पुष्प-मालाएं अर्पित की गयीं, कुछ स्तुतिगान हुए और तालियां बजीं, पर शिक्षा से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर दिमाग खपाने की फुरसत भला किसे थी? ज्ञानार्जन और ज्ञानदान की गुरुकुल परंपरावाले इस देश में शिक्षा और शिक्षक का पथभ्रष्ट होना सबसे भीषण अभिशाप है। ऐसा शिक्षक, जिसमें ज्ञानार्जन की भूख न हो, वह समाज को क्या देगा? ऐसे विजातीय तत्वों के कंधों पर जब समाज को दिशा देने का दायित्व रख दिया गया हो, तब समाज का क्या होगा? ऐसे कुछ गूढ़ सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश न तो सामाजिक चिंतक और शिक्षाशास्त्री कर रहे हैं, न ही सरकार। शिक्षक समाज अपने भौतिक विलास के हित साधन की अंधी दौड में शामिल है, तो वातानुकूलित कमरों में बैठकर शिक्षा की नयी नीति तय करनेवाले नौकरशाह अपने ड्राफ्ट और नीतियों के बोझ तले असली मुद्दों को दफन करने में। शिक्षा का पतन सभी स्तरों पर जारी है, पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह पतन गंभीर चिंता का विषय बन गया है। उच्च शिक्षा का स्तंभ समझा जानेवाला दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस पतन से अछूता नहीं बचा है।

गौरव की परंपरा गुम: आपसी राजनीति, पदों की लालसा तथा किसी भी तरह कुछ हासिल करने की जोड़तोड़ में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिसंख्य शिक्षक फंसे हैं और विश्वामित्र, द्रोणाचार्य तथा शंकराचार्य जैसे गुरुओं की परंपरा इस अंधी दौड़ में खो गयी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विद्वान शिक्षक सुधीश पचौरी ने हाल ही में प्रकाशित अपने लेख में शिक्षकों की हालत का जिक्र करते हुए अपना क्षोभ इस प्रकार व्यक्त किया है, "कभी-कभी शर्म आती है, हमें। क्या हमने कभी पेशे, अपने कर्म के बारे में रोजमर्रा की जरूरतों से परे सोचा है? अध्यापक रणधीर की तरह क्या हमने अपने-अपने धर्म को प्यार किया है? निश्चय ही हमें प्यार न करने देनेवाले हजार विघ्न उपस्थित हैं। पर यही तो आत्मसंघर्ष है जो विघ्नों को नष्ट करता है और विघ्न देनेवालों को नष्ट करता है। विघ्नों ने चाहा कि हम निकम्मे बनें, न पढ़ें, न लिखें। इस तरह हम अपने से बेगाने बने और ठीक उसी तरह बने जैसा उसने चाहा।" ऐसा क्यों हो गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिसंख्य शिक्षक ज्ञानवर्द्धन और ज्ञानदान से विमुख हो गये हैं? इन शिक्षकों के घरेलू बजट में मनोरंजन का कालम तो रहता है, पर पुस्तकों के लिए कोई खर्च नहीं। इसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मार्क्सवादी विचारक मुरली मनोहर प्रसाद सिंह देते हैं, "प्रवक्ता, रीडर तथा प्रोफेसर के पदों पर मनमानी भर्ती की जाने से ऐसे विजातीय तत्व विश्वविद्यालय में आ जाते हैं जिनकी रुचि पढ़ने-पढ़ाने में नहीं होती। वे महज नौकरी करने आते हैं और नौकरी बजाते हैं। विश्वविद्यालय में नौकरी न मिलती, तो परचून की दुकान में बैठ जाते।"

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा तथा शिक्षकों के स्तर में गिरावट के लिए शिक्षकों का एक वर्ग मौजूदा कुलपति मूनिस रजा को जिम्मेदार ठहराता है। सिंह कुलपति पर 'कांग्रेस का पिट्ठू' होने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि रजा ने अपनी कुरसी बचाये रखने के लिए अपने आकाओं—केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हरकिशनलाल भगत और कांग्रेस-इ महामंत्री आस्कर फर्नांडीस को खुश करने के उद्देश्य से इसी

गुट के अध्यापकों में पंजीरी बांटी। उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि कुलपति ने ऐसे १३-१४ शिक्षकों को प्राक्टोरियल बोर्ड में 'फिट' कर दिया है तथा अपने खास दो शिक्षकों, भीम सिंह तथा दीपक मल्होत्रा को क्रमश: सत्यवती सांध्य कालेज तथा दयाल सिंह सांध्य कालेज का उपप्रधानाचार्य बना दिया है। मल्होत्रा को विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी पद पर भी बैठा दिया है। दूसरी तरफ कुलपति 'माया' से बातचीत में इन सब नियुक्तियों को उचित बताते हैं तथा पक्षपात के आरोप को बेबुनियाद। सिंह बताते हैं कि विधि विभाग में कुलपति ने अपने एक खास शिक्षक को प्रोफेसर बनवा दिया। उन्हें चुनाव कमेटी के सामने लाये बगैर सीधे इक्जिक्यूटिव काउंसिल में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करवा कर उनकी नियुक्ति करवा दी और बाद में एक विधि केंद्र का प्रभारी तथा एक कालेज की प्रबंध समिति का अध्यक्ष का ओहदा थमा दिया। ये प्रोफेसर पिछले चार वर्षों से क्लास नहीं ले रहे हैं।

शिक्षकों के धंधे: दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके ६० कालेजों में लगभग ६ हजार शिक्षक हैं। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी तादाद शिक्षकों की नहीं है। इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो विश्वविद्यालय में केवल हाजिरी लगाने आते हैं और पढ़ाने के नाम पर 'रस्म अदायगी' करके अपने अलग-अलग धंधों में लग जाते हैं। कोई जमीन व फ्लैट्स की खरीद-फरोख्त का दलाल है, कोई सहकारी आवास समिति चला रहा है और कोई अपने बाप-दादा के व्यवसाय में अपना समय लगाता है। एक शिक्षक तो अशोक विहार कालोनी स्थित एक मंदिर के मठाधीश बन गये हैं। जो शिक्षक कोई 'साइड बिजनेस' या 'फुल टाइम' धंधा नहीं करते हैं, वे अपना समय प्रधानाचार्यों और विश्वविद्यालय के कतिपय 'वजनदार' लोगों की चाटुकारिता में सार्थक करते हैं।

ऐसा नहीं है कि दिवि में विद्वान शिक्षक नहीं हैं। भीष्म साहनी, डा० केबी भटनागर, मनोरंजन मोहंती और डा० वीरेंद्र कुमार जैसे ख्यातिप्राप्त शिक्षकों ने इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, पर ये नौकरीपेशा शिक्षकों की भीड़ में खोकर रह जाते हैं। अपनी शैक्षणिक साधना में लिप्त विद्वान शिक्षक आमतौर पर विश्वविद्यालय के मामलों में दखल नहीं देते हैं, क्योंकि वे पद पाने के लिए खेली जानेवाली टुच्ची राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। इनकी यह निर्लिप्तता विश्वविद्यालय का कोई हित नहीं करती है, लेकिन विश्वविद्यालय के बिगड़े शैक्षणिक माहौल के लिए इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पतन की परंपरा: विश्वविद्यालय के पतन के लिए शैक्षिक संगठन भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि विश्वविद्यालय प्रशासन। इस विश्वविद्यालय में शिक्षक आंदोलन का इतिहास पलटने से पता चलता है कि १९४३ में ब्रिटिश शासकों द्वारा उच्च शिक्षा पर होनेवाले खर्च में कटौती करने के दृष्टिकोण से इंद्रप्रस्थ कालेज की तीन स्थायी महिला शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाना शिक्षकों के संगठित होने का कारण बना। तब सर मारिस ग्वायर उपकुलपति थे। उनसे अनुमति लेकर काउंसिल हाल में सभी कालेजों के शिक्षकों की पहली बैठक हुई और परदे के पीछे बैठकर ग्वायर ने सारी कार्यवाही सुनी और फिर मामला देखने का वायदा किया। तीनों शिक्षिकाओं को नौकरी में वापस ले लिया गया। यहीं से शिक्षकों को अपने संगठित होने की शक्ति

साक्षात्कार: मूनिस रजा

मुझे तो कहीं गुंडाराज नहीं दिखायी देता

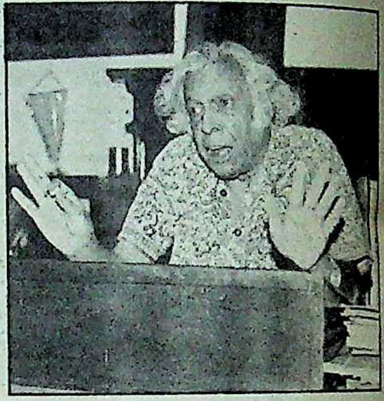

जनाब मूनिस रजा दिवि के कुलपति होने के पूर्व अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे चुके हैं। रजा का यह पांच साल का कार्यकाल २ फरवरी, १९९० को पूरा होनेवाला है। वे दिवि को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मानते हैं और कहते हैं, "समूचे आस्ट्रेलिया में जितने छात्र हैं उतने इस अकेले विश्वविद्यालय में हैं। ऐसे सेहतमंद विश्वविद्यालय में अच्छाइयां हैं, तो बुराइयां भी होंगी।" प्रस्तुत हैं, दिवि के मौजूदा मुद्दों पर उनसे 'माया' की बातचीत के अंश:

माया: ***दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आपके पांच वर्ष पूरे होनेवाले हैं। यह कार्यकाल कैसा रहा?***

मूनिस रजा: *मैंने अपने कार्यकाल मे मुख्यतया तीन बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया है: पहला यह कि शोध के 'थ्रस्ट एरिया' जैसे इकौलाजी (परिस्थिति की), कंप्यूटर साइंस, सुपर कंडक्टिविटी और माइक्रो बायोलाजी आदि क्षेत्रों में काम शुरू कराया है, दूसरा यह कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम को विस्तारित करने का प्रयास किया है, तीसरा मुख्य काम विश्वविद्यालय उद्योग अंत:क्रिया प्रकोष्ठ के जरिए छात्रों का नाता सीधे उद्योगों से जोड़ने और विज्ञान, शिक्षा एवं संचार केंद्र के जरिए विज्ञान की शिक्षा को आम आदमी तक ले जाने की पहल की है। इस केंद्र के प्रतिभाशाली और उत्साही शोध छात्र-छात्राओं ने होशंगाबाद के पिछड़े आदिवासी गांवों में यह सिखाने का काम किया है कि विज्ञान की शिक्षा कैसे प्रदान की जाये और दस वर्षों से यह काम जारी है। मैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के जनसंचार संस्थान के सहयोग से एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाहता हूं। देश के हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान की नयी खोज व तकनीक के बारे में लेख बहुत कम छपते हैं। हम चाहते हैं कि विज्ञान पर एक बुलेटिन तैयार की जाये और अखबारों को भेजा जाये ताकि आम लोगों को यह पता चले कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या काम हुआ और हो रहा है। अखबार जितनी और जैसी चाहें सामग्री इस बुलेटिन से लेकर छापें। इसके अलावा विश्वविद्यालय में ही हम विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी पुस्तकें लिखवाकर हिंदी में छपवा रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं।*

माया: ***शिक्षकों का एक तबका आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने अपने कार्यकाल में कांग्रेस के शिक्षकों को बहुत तरजीह दी है और इसी दृष्टिकोण से प्राक्टर, डीन और प्रोफेसर के पदों पर शिक्षकों को नियुक्त कराया है और काबिल लोगों को नजरअंदाज किया है?***

रजा: *कुलपति का काम यह है कि पदों पर मौजू आदमी को ही चुने। वह कांग्रेसी है या कम्युनिस्ट, उसका ख्याल न रखे। मैंने भी हमेशा यही कोशिश की है। अब प्रोवोस्ट पदों पर नियुक्ति को ही लीजिये, इस पद पर तो ऐसा शख्स होना चाहिये जो छात्रों से सख्ती और नरमी दोनों तरह से पेश आये और उनका पूरा खयाल रखे। प्रोवोस्ट (विभागाध्यक्षों के) पदों के लिये सात वरिष्ठ अध्यापकों को चुना गया है, जिनमें मनोरंजन मोहंती, प्रेम सिंह, एमके रे, एके सिन्हा, अणिमा सेन, फीरोज अहमद और केजी मुखर्जी। इनमें देख लीजिये कि कितने कांग्रेसी हैं? ये सभी काबिल लोग हैं।*

माया: ***चीनी और जापानी अध्ययन विभाग के प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति को लेकर***

का भान हुआ। कांति शास्त्री, स्वरूप सिंह और केएम राज ने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का संविधान तैयार किया। उस समय दिवि बहुत छोटा था। इंद्रप्रस्थ, श्रीराम कालेज आफ कामर्स, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, रामजस और दिल्ली कालेज मिलाकर विश्वविद्यालय बना था, जिनमें पांच-छह सौ छात्र-छात्राएं पढ़ते थे। लगभग ढाई दशक तक दिवि का शिक्षक संघ एक 'क्लब' से अधिक कुछ नहीं था और इसका स्वरूप ट्रेड यूनियन का नहीं बना था। सत्तर के दशक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के साथ-साथ संगठन का स्वरूप बहुत तेजी से बदलना शुरू हुआ और इसके चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी शुरू हो गया।

शिक्षक जनसंघ, (अब भाजपा), कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियों का झंडा थामकर गुटों में बंट गये। १९७१ में पहली बार पूरी तरह ध्रुवीकृत चुनाव हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुमारेश चक्रवर्ती, जनसंघ के ओमप्रकाश कोहली और कांग्रेस के यूएस माथुर के बीच मुकाबले में कुमारेश जीते। कुमारेश के आक्रामक युवा नेतृत्व में शिक्षक आंदोलन का तेवर बदला। वामपंथी रुझानवाले शिक्षक इस विश्वविद्यालय पर हावी रहे और बीच के तीन कार्यकालों को छोड़कर वामपंथी उम्मीदवार ही अध्यक्ष पद पर जीतता रहा। सत्तर के दशक के प्रारंभ तक शिक्षक संघ हड़ताल व आंदोलन के जरिए अपनी मांग मनवाने की परंपरा निभाता रहा, लेकिन मेज के सामने बैठकर एक दूसरे का स्वार्थ साधने की परंपरा इसके बाद पनपने लगी। इस दौर के कुलपतियों ने विश्वविद्यालय में शांति बनाये रखने, किसी का भला करने या बदमगजी पैदा होने से बचने की नीयत से शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की सिफारिशों को मानना शुरू कर दिया था। वहां से शुरू हुई, यह परंपरा आज तक कायम है और फल-फूल रही है।

विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी योग्यता के बजाय राजनीतिक आधार पर होने से इन कुलपतियों के लिए अपनी कुरसी बचाये रखने के लिए अपने राजनीतिक आकाओं को प्रसन्न रखना भी जरूरी हो जाता है। यहीं से तमाम गड़बड़ियों की शुरुआत होती है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को 'नाक में दम करने की अपनी शक्ति' का आभास है और वे इसका फायदा हमेशा उठाते रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले विश्वविद्यालय के एक रीडर ने अपने अधीन शोध कर रहे शिक्षक नेता के संपर्क का फायदा उठाकर प्रोफेसर का पद हासिल किया। विश्वविद्यालय काफी हाउस में अड्डेबाजी करते पुराने व नये शिक्षक नेता अपनी-अपनी राजनीतिक हैसियत की डींगें मारते रोज दिखायी पड़ जायेंगे। इन नेताओं के बारे में आम राय बन गयी है कि ये पूर्णकालिक नेता हैं, पढ़ाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही शैक्षणिक मसलों पर ये चिंतन ही करते हैं। हाल ही संपन्न शिक्षक संघ के चुनाव से पहले शिक्षकों के एक वर्ग ने विश्वविद्यालय के कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज के प्रधानाचार्य आरडी पंवार के खिलाफ जेहाद छेड़कर उन्हें पदच्युत करने की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया। पवार लगभग नौ वर्षों से इस कालेज के अस्थायी प्रधानाचार्य हैं और उनके समय में कालेज का तीव्र विकास हुआ तथा कालेज का परीक्षा-परिणाम विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रतिशत से दो गुना अधिक रहा। पिछली फरवरी तक पवार एक सक्षम प्रधानाचार्य के रूप में शांतिपूर्वक काम करते रहे, पर जब उनका पद स्थायी होने की चर्चा शुरू हुई, तो शिक्षकों के एक

बड़ा बावेला मचा था। उसमें भी आप पर सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार को नजरअंदाज करने का आरोप है?

रजा: *उस पद पर काशीराम शर्मा की नियुक्ति बिलकुल सही है। वे बहुत काबिल आदमी हैं। आपका इशारा मनोरंजन मोहंती की तरफ है, जिन्होंने भी इस पद के लिये आवेदन दिया था। लेकिन उन्हें इस पद के लिए आवेदन देने की क्या आवश्यकता थी? वे तो अपने ही सुझाये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत उपयोगी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तो हैं ही। सेलेक्शन कमेटी को भी उनका आवेदन देखकर आश्चर्य हुआ था। इतने योग्य आदमी को उनके काम से हटाकर कहीं और ले जाना उचित नहीं था। मोहंती की काबिलीयत के लिये मेरे दिल में बहुत इज्जत है।*

माया: ***विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी का पद कांग्रेस के किसी नेता को खुश करने के लिए सृजित करने और एक कांग्रेसी अध्यापक की नियुक्ति करने का भी आप पर आरोप है?***

रजा: *यह पद तो बहुत वर्षों से है। काफी दिनों तक योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़ा रहा। फिर इस पद पर मैं ऐसे आदमी को तो रखूंगा ही जो मीडिया में विश्वविद्यालय की सही तस्वीर पेश करे।*

माया: ***लेकिन कहा जाता है कि जिस शिक्षक की नियुक्ति इस पद पर की गयी, उन्हें इसी विश्वविद्यालय के छात्र होने के दौरान गुंडागर्दी के आरोप में विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की नोटिस जारी हो गयी थी?***

रजा: *यह बिलकुल झूठा इल्जाम है। उन पर कोई केस नहीं था।*

माया: ***शिक्षकों के एक वर्ग का कहना है कि आपने अपना पद सुरक्षित बनाने के लिए शिक्षकों को ऊंचे पदों का लालच देकर पालतू बनाने की मुहिम चलायी और कांग्रेस-इ पार्टी से ताल्लुक रखनेवाले छात्रों को शह देकर विश्वविद्यालय में 'गुंडाराज' कायम किया।***

रजा: *(हंसते हुए) मैंने किस शिक्षक को पालतू बनाया है, भला? विश्वविद्यालय के उच्च पदों पर नियुक्ति का काम इक्जिक्यूटिव काउंसिल करती है और सेलेक्शन कमेटी उम्मीदवार तय करती है। यह अकेले कुलपति के हाथ में नहीं होता। रही 'गुंडाराज' की बात, सो तो मुझे विश्वविद्यालय में कहीं दिखायी नहीं देती। पिछले लगभग पांच वर्षों से तो छात्रसंघ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। कांग्रेस का अजय माकन तो पांच वर्ष पहले था। तो क्या भाजपावालों को भी मैं ही जिताता रहा हूं? और फिर जो छात्र कहीं गड़बड़ या हिंसा करते हैं, उन्हें क्या मैं ही शाबासी देता हूं और पीठ थपथपाता हूं?*

माया: ***विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय में आंदोलन का स्वरूप क्या होना चाहिए?***

रजा: *उस्तादों (शिक्षकों) के संगठन का काम यह है कि वे यह देखें कि इल्मी काम को किस तरह बढ़ाया जाये तथा उस्तादों के के हितों की रक्षा हो। लेकिन अब यह संगठन दूसरे काम की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। हड़ताल का हथियार तो शिक्षकों के लिए है ही नहीं। यह हथियार तो औद्योगिक क्षेत्र में वेतन और मुनाफे का अनुपात तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हड़ताल से कुलपति का नहीं, वरन छात्रों का नुकसान होता है। पढ़ाने की जिम्मेदारी एक नैतिक सवाल है जिस पर शिक्षकों को सोचना चाहिए।*

मेरी निजी राय है कि सरकार को ऐसी अदालत बनानी चाहिए जो सरकार से ऊपर हो और जहां शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और अदालत का फैसला मानने को सरकार बाध्य हो।

माया: ***आप कुलपति के पदभार से मुक्त होने पर क्या करने की योजना बना रहे हैं?***

रजा: *३ फरवरी, १९९० की सुबह नौ बजे मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अपने कमरे में आपको मिलूंगा। मैं उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एमेरिटस (विशेष योग्यता प्राप्त) हूं और यह ऐसी नौकरी है जिससे कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब मैं लेक्चरर था, तब मैंने अपने से वायदा किया था कि हर साल तीन मजमून और हर तीन साल में एक किताब लिखूंगा। खुदा का शुक्र है कि यह वायदा मैं आज तक निभाता रहा हूं। फिलहाल मेरी चार किताबें प्रेस में हैं। इनके अलावा मैं फुर्सत पाने पर दो किताबें और लिखना चाहता हूं।*

—बिशन कुमार

गुट को उनमें तमाम खामियां नजर आयीं और उन पर प्रशासनिक मामलों के अलावा चारित्रिक स्तर पर भी आरोप लगाये जाने लगे। उसी गुट की एक शिक्षिका ने तो पवार पर यह आरोप भी लगा दिया कि वे (पवार) उनको अपनी हविश का शिकार बनाना चाहते हैं। उस कालेज में लगभग ६० शिक्षकों में ३६ महिला शिक्षक हैं और पिछले नौ वर्षों में कभी किसी ने पवार के चरित्र पर उंगली नहीं उठायी थी।

कालेज स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश और महामंत्री जीएस जाली से जब 'माया' ने इस बावत पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह सब एक महिला शिक्षक की स्थायी नियुक्ति की खातिर दबाव डालने के लिए किया गया। उनके अनुसार कालेज के अधिसंख्य शिक्षक पवार के साथ हैं और गुट विशेष की इस गंदी राजनीति के खिलाफ हैं। आखिर वही हुआ। पवार को हटाने का मुद्दा शिक्षक संघ के ताजा चुनाव में प्रमुखता से उठाया ही नहीं गया और एक राजनीतिक चाल विफल हो गयी।

शिक्षकों का मोहभंग : विश्वविद्यालय का इतिहास इस तरह के घात-प्रतिघात के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इन राजनीतिक चालों से कभी किसी शिक्षक का भला हो जाता है, पर हमेशा नुकसान पढ़ाई के प्रति गंभीर छात्रों का ही होता है। शिक्षक आंदोलन के पथभ्रष्ट हो जाने से शिक्षकों के एक बड़े वर्ग का इससे मोहभंग हो गया है और वे तटस्थ रहकर अपनी भूमिका तय करने पर विचार करने लगे हैं। ऐसा ही एक प्रयास इधर हुआ है और डा० जेपी शर्मा के संयोजकत्व में प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। इसके एक सक्रिय कार्यकर्ता श्रीराम कालेज आफ कामर्स के प्रवक्ता चंद्रशेखर शर्मा मानते हैं कि शिक्षक आंदोलन का स्वरूप बदलने की महती आवश्यकता है और नेतृत्व से निराश शिक्षक अपनी समस्याओं के लिए नया मंच तलाश करने की जरूरत महसूस करने लगे हैं।

शिक्षक संघ के वर्तमान अध्यक्ष मुरली मनोहर प्रसाद सिंह इस जरूरत के प्रति सजग हैं और महसूस करते हैं कि शिक्षक संघ को ट्रेड यूनियन के रूप में अपना फर्ज निभाने के अलावा शिक्षक समाज के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षकों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उनका कहना है कि देश में जहां एक सुनियोजित साजिश के तहत शिक्षकों को पालतू बनाया जा रहा है, वहीं साम्राज्यवादी देश ज्ञान पर अपना वर्चस्व कायम कर तीसरी दुनिया के देशों को उपनिवेशवादी गुलामी में जकड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं।

बहरहाल, इन भारी भरकम सवालों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है और छात्रों का शिक्षा की उपयोगिता से विश्वास उठता जा रहा है।

—बिशन कुमार

साक्षात्कार : मुरली मनोहर प्रसाद सिंह

'कुलपति गुंडाराज चला रहे हैं'

माया : *दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने पर आपकी क्या भावी योजनायें हैं?*

मुरली मनोहर प्रसाद सिंह : *विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा-शर्तों के बारे में पिछले वर्षों में जारी आदेश और कानून से साफ जाहिर है कि उनके खिलाफ नीतिबद्ध आक्रमण हो रहा है। इसके तहत उठाये जा रहे कदम महज अफसरों के दिमाग की खब्त नहीं हैं। इनके खिलाफ अगर प्रतिकारात्मक आंदोलन न छेड़ा गया, तो शिक्षकों का स्वाधीन बुद्धिजीवियों के रूप में अपना अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और कोई भी प्रतिभाशाली युवक इस पेशे में नहीं आना चाहेगा। शिक्षकों ने नयी कार्यकारिणी को चुनकर यह दायित्व सौंपा है और मुझे इसका निमित्त बनाया है। मैं भरसक इसे पूरा करूंगा।*

माया : *शिक्षक आंदोलन को कैसा स्वरूप आप देना चाहते हैं?*

सिंह : *देखिये, शिक्षक आंदोलन किसी द्वीप का प्रीतिभोज नहीं है। यह तो देश के लोकतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न अंग है और मूल्योन्मुख आंदोलन के साथ इस काम का सीधा संबंध है। शिक्षक आंदोलन का दो दिशाओं में देखना जरूरी है, एक ओर, जहां शिक्षकों के हितों, सेवा-शर्तों तथा प्रशासनिक पहलुओं पर आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ, हमें ज्ञानदान करने की भूमिका निभानेवाले शिक्षकों को साम्राज्यवादी देशों की 'ज्ञान को अपने यहां सीमित करने की साजिश' के प्रति भी जागरूक करना है, जिसके परिणामस्वरूप तीसरी दुनिया के देशों से प्रतिभा का पलायन होता है। अपने छात्रों पर हम जो हजारों रुपए खर्च करते हैं, वह हमारी नयी पीढ़ी के काम नहीं आ पाता, क्योंकि साम्राज्यवादी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े-बड़े प्रलोभन देकर उन्हें अपने यहां खींच लेती हैं। आज की दुनिया में ज्ञान भी एक कमोडिटी बन गया है और साम्राज्यवादी देश इससे तीसरी दुनिया के देशों को अलग-थलग बनाये रखने का खेल खेल रहे हैं। इस विश्वव्यापी साजिश को परास्त करना बहुत आवश्यक है।*

माया : *इस साजिश के सफल हो जाने के क्या परिणाम होंगे?*

सिंह : *साजिश के सफल होने पर ज्ञान साम्राज्यवादी देशों में सिमट कर रह जायेगा और उपनिवेशवाद के रूप में हमारी गुलामी कायम रहेगी।*

माया : *दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूदा हालात कैसे हैं?*

सिंह : *सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे विजातीय तत्व शिक्षक पद पर भरे जा रहे हैं, जिनको ज्ञानार्जन और ज्ञानदान में कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोग दुकान पर बैठने के काबिल हैं। इसमें सीधा कुलपति का हाथ है। उदाहरण के तौर पर दिवि में कुलपति ने प्राक्टोरियल बोर्ड में ऐसे शिक्षकों को भर लिया है जिनका पढ़ाने से कोई लेना-देना नहीं है।*

माया : *इससे कुलपति को क्या हासिल हुआ?*

सिंह : *इस तरह के लोगों को अपने इर्द-गिर्द एकत्र करके कुलपति ने संगठित शिक्षक आंदोलन के खिलाफ गुंडावाहिनी बनाने का काम किया है। विश्वविद्यालय में 'गुंडा गिरोह राज' कायम हो गया है। कुलपति सिर्फ लफ्फाजी करते हैं।*

माया : *शिक्षक आंदोलन इसका किस तरह से मुकाबला करेगा?*

सिंह : *ज्ञान-अर्जक और ज्ञानदाता की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पदों पर योग्य लोगों की नियुक्ति हो। जब इन पदों पर 'सब स्टैंडर्ड' लोगों को बैठा दिया जाता है, तो शिक्षकों में रोष पैदा होता है और हमें अपना अहम मुद्दा छोड़कर इन मामलों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। यह कुलपति की साजिश है। ऐसे तिकड़मी लोगों के इन पदों पर आसीन रहते हम कितने भी प्रवचन झाड़ें, शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल तो शैक्षणिक नेता होता है, अगर वही तीसरे दर्जे का हो, तो भला गुणात्मक सुधार की बात क्या की जाये? हम ऐसी हर नियुक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे।*

—बिशन

यों और उन
रित्रिक स्तर
गुट की एक
प भी लगा
हविश का
त में लगभग
और पिछले
चरित्र पर

के अध्यक्ष
ाली से जब
बताया कि
यी नियुक्ति
किया गया।
शिक्षक पवार
दी राजनीति
ार को हटाने
में प्रमुखता से
नीतिक चाल

विद्यालय का
के उदाहरणों
ालों से कभी
, पर हमेशा
का ही होता
हो जाने से
भंग हो गया
का तय करने
प्रयास इधर
योजकत्व में
न किया गया
राम कालेज
र्मा मानते हैं
ने की महती
राश शिक्षक
तलाश करने

ध्यक्ष मुरली
प्रति सजग हैं
संघ को ट्रेड
ने के अलावा
ुनौतियों का
ागरूकता पैदा
है कि देश में
न शिक्षकों को
ाज्यवादी देश
ीसरी दुनिया
में जकड़ने का

सवालों के
उपयोगिता
शिक्षा की
रहा है।
बिशन कुमार

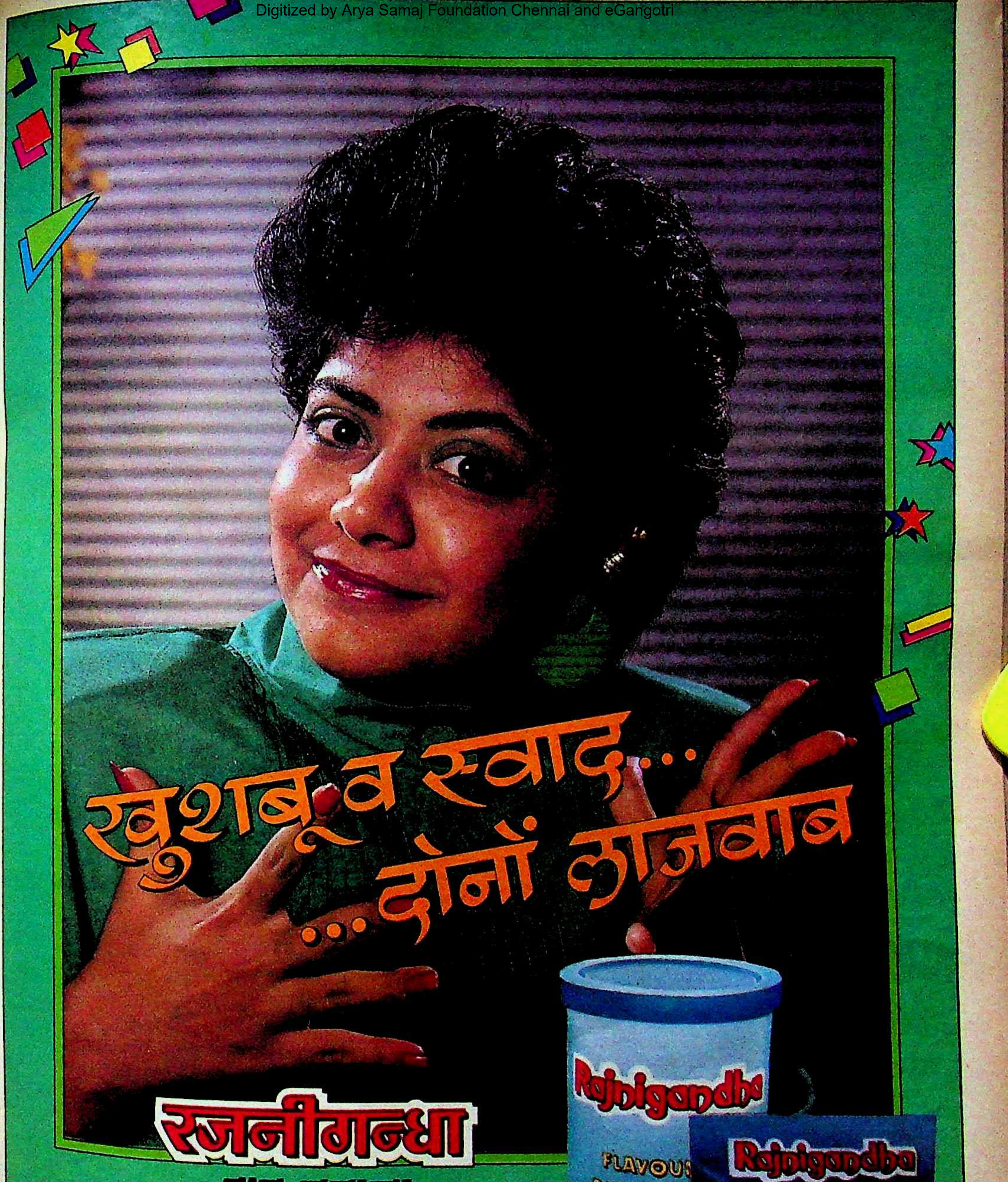
खुशबू व स्वाद...
...दोनों लाजवाब
रजनीगन्धा
पान मसाला
उत्तम सुपारी, इलायची व कत्थे से निर्मित
Rajnigandha
FLAVOUR
PAN MAS
SUPERB IN FRESHNESS
Rajnigandha
FLAVOURED
PAN MASALA
SUPERB IN FRESHNESS AND TASTE
FUSION

श्रद्धा से झुकीं हमारी आंखें

हुए दर्शन. सफ़ल हुई यात्रा.

मद्धिम प्रकाश और भक्ति के संगीत में अलौकिक था मंदिर का भीतरी दृश्य.

उस दिव्य मूर्ति के सामने हमने सीस झुकाया.

पर शर्म से भी नीचे हुए हमारे सर.

मंदिर की सीढ़ियों पर हमने देखा था कुछ शराबियों को झगड़ते हुए.

दो 'भक्तों' ने रास्ते में बियर चढ़ा ली थी.

फिर हुई उनमें झड़प.

पवित्रता में अपवित्रता

और फिर उस पवित्र घाट में हुए अपवित्रता के दर्शन.

पानी बह रहा था.

कुछ मर्द औरतों को घूर रहे थे.

कुछ कुल्ला करके थूक रहे थे, पानी उछाल रहे थे, बच्चों को शौच करा रहे थे.

और वहीं से लोग स्नान करके जा रहे थे मंदिर में दर्शनों के लिए...

यह धरोहर आपकी है इसे बचाइए

यात्रा सिर्फ़ सैर नहीं, एक खोज भी है.

भारत की अनमोल विरासत: समूची दुनिया में बेजोड़.

अनगिनत क़िलों, स्मारकों, तीर्थों में गूंजती हुई 5 हज़ार साल की गौरव-गाथा.

पर्यटन विभाग भारत सरकार

और शर्म से भी

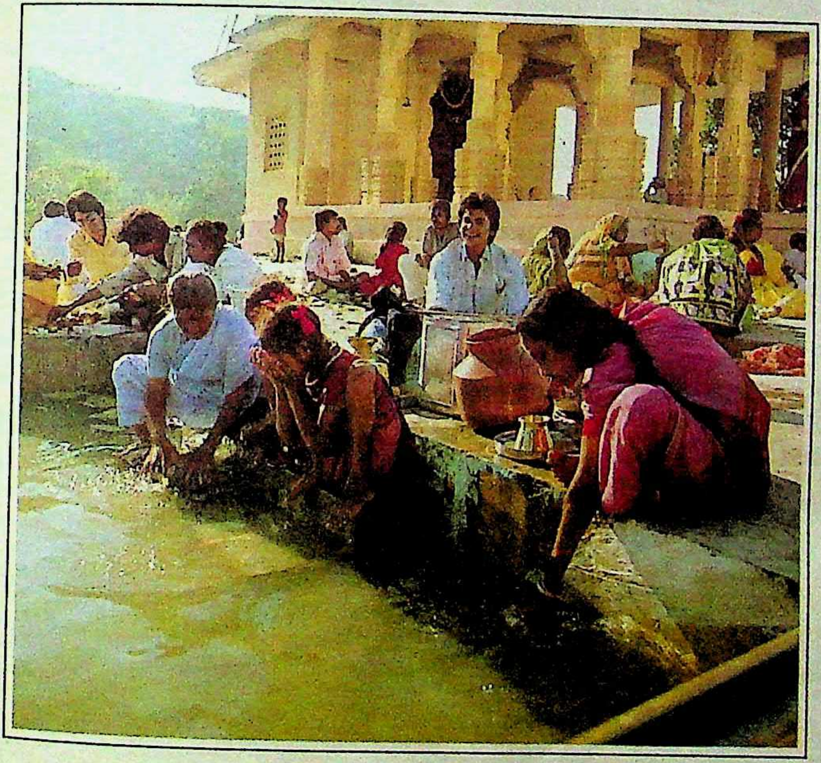

और विविधता और वैभव से भरी प्रकृति.
कितने ही रंग और रंगतों में मोहती.
कोई किसी स्मारक को बदशक़्ल करता दिखे, किसी पूजास्थल या तीर्थ का अपमान करे, या अपने माहौल को बिगाड़ता गंदा करता नज़र आये तो आप चुप न बैठिए.
उसे समझाइए.
उसे रोकिए.
उसकी शिकायत कीजिए.

अपनी अनमोल विरासत को बचाइए.
सिर्फ़ यही है आपकी धरोहर.

हम ही रचेंगे
हम ही रखेंगे
अपना भारत सुन्दर

Department of Tourism Government of India

लैवेन्डर मिस्ट
एक लाजवाब टैल्क
Cuticura Lavender Mist
मुफ़्त
क्यूरोलीन
त्वचा-रक्षक एन्टीसेप्टिक क्रीम
२० ग्राम - लैवेंडर मिस्ट
४०० ग्रा. के हर पैक के साथ.
यह मौका उत्तर-भारत और पूर्व-भारत के लिए - सिर्फ स्टॉक खत्म होने तक.

जनरल सुंदरजी

वर्जित क्षेत्र की ओर राजनीति का बढ़ता पांव

'एक भ्रष्ट सरकार और एक गैरजिम्मेदार विपक्ष के बीच जनरल सुंदरजी ऐसे हरक्यूलिस के रूप में उभरे हैं जो अकेले ही उस सारी बजबजाती गंदगी को साफ कर सकते हैं, जिसे राजनेता अपने पीछे छोड़ गये हैं...यह निश्चय ही लोकतंत्र के लिए सुखद दिन नहीं है। क्या हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिसे छोड़ने के लिए पाकिस्तान कसमसा रहा है?'

—निखिल चक्रवर्ती

एक सप्ताह बाद सही, लेकिन अच्छा हुआ कि पंजाब कांग्रेस-इ अध्यक्ष बेअंत सिंह को सद्बुद्धि आ गयी और उन्होंने अपने उस कथित बयान का खंडन कर दिया, जिसमें उन्होंने १९८४ में स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में (आपरेशन ब्ल्यू स्टार के तहत) हुई सैन्य कार्यवाही के लिए अकेले जनरल सुंदरजी को ही जिम्मेदार ठहराया था। पंजाब के ठेठ देहाती इलाके (जगरांव) में संपन्न हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बेअंत सिंह द्वारा सुंदरजी पर लगाया गया उक्त कथित आरोप अनेक अखबारों में प्रकाशित हुआ था और इसका खंडन आने तक इस वक्तव्य की पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि एक जनरल को ऐसे फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिससे उसका दूर-दूर तक वास्ता नहीं था।

अपनी पुरजोर कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके सहयोगी बोफोर्स तोप सौदों में ली गयी दलाली के आरोप की कालिख को धो नहीं सके थे कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरजी द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन ने तहलका मचा दिया कि उन्होंने दलाल का पता लगाने के लिए बोफोर्स कंपनी से तोपों का सौदा रद्द करने की पेशकश की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया। सुंदरजी के वक्तव्य का आशय यही निकलता था कि सरकार दलाल का पता लगाने के बारे में ईमानदार नहीं है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि देश के अच्छे-बुरे वक्त में सैन्य कार्यवाही से संबंधित सारे फैसले राजनीतिक नेतृत्व लेता है और आपरेशन ब्ल्यू स्टार के मामले में तो खुफिया जानकारियां एकत्र करने तक का कार्य सेना ने नहीं अन्य एजेंसियों ने किया था और सेना को स्पष्ट आदेश थे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अतः यह जानते हुए कि जनरल सुंदरजी आपरेशन ब्ल्यू स्टार के सूत्रधार नहीं हो सकते, इसके बावजूद यदि कोई उन पर स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही की जिम्मेदारी थोपता है, तो इससे बढ़कर बेसमझी की कोई बात नहीं हो सकती। ऐसी बातों से उन आतंकवादियों को और शह मिलती है जो ब्ल्यू स्टार से जुड़े सैन्य अधिकारियों की जान के पीछे पड़े हैं। जनरल वैद्य पहले ही उनका निशाना बन चुके हैं। हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास है और उनके शौर्य व निष्ठा का कोई सानी नहीं है। देश के अनेक संस्थानों का नैतिक पतन हो चुका है—लेकिन उनके बीच में 'भारतीय सेना' ही है जो अपना सिर ऊंचा करके खड़ी है। इसीलिए यह अच्छा होगा कि सेना को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाये।

देश का गौरव सर्वोपरि है: जनरल सुंदरजी

> **सेना को नागरिक सेनाओं जैसे कार्यों का जिम्मा सौंपने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे फौज के जवानों में लड़ने का माद्दा कम हो जाता है और वे सैन्य शिविरों के कठिन प्रशिक्षण और अभ्यास से कट जाते हैं। अहमदाबाद का उदाहरण सबके सामने है। यहां के उपनगरीय क्षेत्रों में उपद्रवों को शांत करने के इरादे से एक साल के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन फौजियों में नगरीय जीवन की वे बातें भी घर कर गयीं जो मोर्चे पर जवान की कमजोरी बन जाती हैं।**

राजनीतिकरण का खतरा: सेना का राजनीतिकरण बड़ी धीमी, लेकिन सतत गति से होता है और एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाये, तो अचानक एक दिन पता चलता है कि सेना ने राजनीति अपने हाथ में ले ली है। यद्यपि भारतीय सेना अभी राजनीति से बहुत दूर है, लेकिन जो आसार बन रहे हैं, वे परिस्थितियों को गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकते हैं।

सेना को नागरिक सेवाओं जैसे कार्यों का जिम्मा सौंपने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे फौज के जवानों में लड़ने का माद्दा कम हो जाता है और वे सैन्य शिविरों के कठिन प्रशिक्षण और अभ्यास से कट जाते हैं। अहमदाबाद का उदाहरण सबके सामने है। यहां के उपनगरीय क्षेत्रों में उपद्रवों को शांत करने के इरादे से एक साल के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन फौजियों में नगरीय जीवन की वे बातें भी घर कर गयीं जो मोर्चे पर जवान की कमजोरी बन जाती हैं। आपरेशन ब्ल्यू स्टार के पूर्व पंजाब में भी सेना तैनात की गयी थी और वहां भी सेना के सामने वही समस्याएं आयीं। आजादी के पहले अधिकांश सैन्य छावनियां शहर से दूर स्थापित की गयी थीं। लेकिन समय गुजरने और शहरों की आबादी के बढ़ते जाने से अब ये छावनियां शहर की हद में आकर उसका एक हिस्सा बन चुकी हैं।

श्रीलंका में भारतीय सेना की कार्यवाही के संबंध में अपनाये गये रवैये की भी आलोचना हुई है। संभवतः इसी कारण सेना के कुछ अवकाशप्राप्त वरिष्ठ अधिकारियों ने समाचार पत्रों के स्तंभों के जरिए यह दलील दी है कि परंपरा के अनुसार श्रीलंका में घायल हुए या मारे गये भारतीय जवानों के नाम समाचार पत्रों में

जनरल वीएन शर्मा

सेनाध्यक्ष : कैसे-कैसे ?

फील्ड मार्शल एस मानेक शा

तब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उधमपुर के एक सैन्य ठिकाने का मुआयना करते वक्त जनरल पीएस भगत ने उनसे सीधे पूछा था, "मैडम आप मुझे कब सेनाध्यक्ष बना रही हैं अथवा क्या आपके दिमाग में कोई अन्य बात है?" एक अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल उस प्रसंग का स्मरण करते हुए बताते हैं, "यह सुनकर श्रीमती गांधी जनरल भगत को कमांड हाऊस 'तारा माउंट' में ले गयी और उनसे बोली, "मैं (तत्कालीन) सेनाध्यक्ष और सुरक्षा सचिव के बीच चल रही 'अहं' की लड़ाई से आजिज आ चुकी हूं। यदि आप सेनाध्यक्ष बन गये, तो ऐसे झगड़े फिर उठ खड़े होंगे।" जनरल भगत के सेवानिवृत्त होने में तब छह मास का समय रह गया था। तत्कालीन सुरक्षा सचिव सरीन और सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेक शा के बीच चल रही टकराहट तब जगजाहिर थी।

स्पष्ट है कि सेनाध्यक्ष के चयन में अनेक बातों पर गौर किया जाता है। एक वरिष्ठ कमांडर के अनुसार, "सेनाध्यक्ष के पद के लिए मेजर जनरल के रैंक से ही अफसरों का चयन हो जाता है और सेना के कमांडरों की नियुक्तियां इस तरह सावधानी पूर्वक सुनियोजित की जाती हैं, जिससे वही कमांडर उभरकर आ सके, जिसे सरकार सेनाध्यक्ष बनाना चाहती है।" जनरल बीएम कौल को तात्कालिक सेनाध्यक्ष जनरल केएस थिमैया पसंद नहीं करते थे, लेकिन कौल को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता रहा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरकार चाहती थी कि कौल सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन १९६२ के चीनी-हमले ने कौल के सेनाध्यक्ष बनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल, एक सैन्य अधिकारी का आरोप है कि चौथी पैदल सेना के प्रमुख के रूप में जनरल कौल ने अपने फौजियों का इस्तेमाल मुख्यतः सैन्य अधिकारियों के लिए आवास बनवाने में किया। यह सब प्रशंसनीय कार्य था, लेकिन इसी वजह से उनके फौजी युद्धाभ्यास से दूर रहे और जब चीन ने हमला किया, तो ये जवान मोर्चे से नीचे उतर आये। बहरहाल, सेनाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में जनरल भगत और जनरल सिन्हा के मामलों को छोड़कर कभी कोई गंभीर विवाद खड़ा नहीं हुआ। वस्तुतः जनरल सिन्हा की वरीयता के उल्लंघन से तो पूरे देश में हलचल मच गयी थी। और यह खबर अखबारों की सुर्खिया बनी थी, क्योंकि जनरल सिन्हा ने त्यागपत्र देकर अपने साथ हुए पक्षपातपर्ण रवैये का विरोध करने के लिए आम जनता के बीच जाने का रास्ता अख्तियार किया था।

सामान्य रूप से माना जाता है कि जनरल भगत को इसी कारण सेनाध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि वे बहुत ताकतवर थे और अपवादस्वरूप सेना में बेहद लोकप्रिय थे। उनके अधीन काम कर चुके एक अवकाश प्राप्त मेजर जनरल का तो यहां तक कहना था, "वे हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनाध्यक्षों में शुमार किये जाते।" जनरल सिन्हा किन्हीं अन्य वजहों से सेनाध्यक्ष नहीं बनाये गये थे। उनके परिवार के राजनीतिक ताल्लुकात थे और यही उन्हें सेनाध्यक्ष के पद से दूर रखने का प्रमुख कारण था। नौकरशाही भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। ले०ज० मैथ्यू के अनुसार, "उनमें दिमाग था—बोलने, लिखने और यहां तक कि जोड़तोड़ में वे नौकरशाहों पर भारी पड़ते थे।" लेकिन जिस तरीके से जनरल सिन्हा को बताया गया कि उन्हें नहीं, बल्कि जनरल एस वैद्य को सेनाध्यक्ष बनाया जायेगा—उससे उन्हें सर्वाधिक चोट पहुंची थी।

हुआ यह था कि जनरल सिन्हा को यह संकेत देकर साउथ ब्लाक लाया गया था कि उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया जायेगा, लेकिन जनरल वैद्य से टेलीफोन पर बात करते हुए तत्कालीन सेनाध्यक्ष केवी कृष्णराव ने अचानक जनरल सिन्हा से कहा कि वे जनरल वैद्य को बधाई दें, क्योंकि उन्हें (जनरल वैद्य) सरकार ने सेनाध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। अनेक जनरलों का निजी बातचीत में मानना है कि जनरल सिन्हा के साथ हुए इस व्यवहार के विरोधस्वरूप जनरल वैद्य को सेनाध्यक्ष बनने से इनकार कर देना चाहिए था।

बहरहाल, जनरल भगत और जनरल सिन्हा के मामलों को छोड़कर शायद ही कभी सेनाध्यक्ष के चयन पर विवाद उठा हो और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि सरकार और सेनाध्यक्ष के बीच कोई गंभीर मतभेद पैदा हुए हों। भूतपूर्व सुरक्षा सचिव गोविंद नारायण ने 'माया' को बताया, "गृह और सुरक्षा सचिव के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और सरकार के बीच शानदार तालमेल रहा। हम उनकी योग्यता-क्षमता का आदर करते थे और वे हमारा। सर्वोच्च पदों पर 'अहं' की टकराहट स्वाभाविक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके कारण कोई बड़ा विवाद उठा हो या संदेह की स्थिति पैदा हो।"

सरकार को सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया के कार्यकाल के दौरान थोड़ी परेशानी हुई थी। वे एक शानदार फौजी थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था, लेकिन उनकी तत्कालीन रक्षामंत्री कृष्णा मेनन से नहीं पटती थी। अवकाशप्राप्त एक वरिष्ठ जनरल ने 'माया' को बताया, "जनरल एसपीपी थोराट ने एक बार कहा था कि यदि जरूरी समझा जाता, तो आगरा से दिल्ली जाने के मार्ग को बंद करने तक की योजना बन गयी थी। पैराशूट ब्रिगेड तब आगरा में थी और सेना की क्रेक युनिट (विशेष हमलावर टुकड़ी) झांसी में केंद्रित थी।" साउथ ब्लाक स्थित कुछ अधिकारियों के लिए जनरल जेएन चौधरी भी चिंता का विषय थे, क्योंकि वे भी सेना में बहुत लोकप्रिय थे और कुशल व्यूहरचनाकार थे।

यह एक रोचक तथ्य है कि जनरल सुंदरजी ही ऐसे सेनाध्यक्ष थे जो प्रधानमंत्री और रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह के बेहद करीब थे। ले०जं० मैथ्यू थामस का कहना है, "इन तीनों की तिकड़ी प्रसिद्ध थी और उनके परस्पर बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि तीनों की मान्यता थी कि भारत में एक बड़ी विश्वशक्ति बनने की पूरी संभावना है।" तीनों इस बात पर सहमत थे कि दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन यह जनरल सुंदरजी ही हैं, जिनके अचानक किये गये रहस्योद्घाटनों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ऐसी परेशानी में डाल दिया, जिससे निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। प्रसिद्ध 'टाइम' पत्रिका ने भी लिखा, "जनरल सुंदरजी के बयानों ने राजीव गांधी के इस दावे का खंडन कर दिया है कि बोफोर्स से तोप सौदा रद्द कर देने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती।" इससे देश के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा भी अपने को विषम परिस्थिति में पा रहे होंगे। वे भी एक कठिन योद्धा हैं। इसी कारण यह माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार को बता दिया है कि वह पूर्व सेनाध्यक्ष के प्रति कठोर रवैया न अपनाये।

बहरहाल, यह तय है कि सरकार भविष्य में रक्षा-सौदों में बड़ी सावधानी बरतेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि हथियारों की खरीद में जनरलों की भूमिका के संबंध में सरकार पुनर्विचार कर रही हो। दूसरी ओर, बताया जाता है कि सेना के अफसर भी चिंतित हैं कि सरकार द्वारा किये गये किसी सौदे के विवादास्पद होने पर वे स्वयं को उससे कैसे दूर रखें? —**नवनीता सरकार द्रोण**

प्रकाशित होने चाहिए। सेना के जवान को यह अनुभव करने का पूरा अधिकार है कि उनका देश उनकी कुर्बानी का सम्मान करता है और इसके लिए वह सेना का ऋणी है।

श्रीलंका के साथ ही मालदीव में हुई भारतीय सेना की कार्यवाही से सेना के जवान पहली बार यह अनुभव लेकर लौटे हैं कि सेना के बल पर सरकारें टिकती हैं और यही अनुभव वह पहला कदम है जो सेना के राजनीतिकरण की ओर बढ़ता है। मालदीव में भारतीय सेना एक ऐसे देश की मदद के लिए गयी थी, जहां की मौजूदा सत्ता का तख्ता पलट गया था। स्वदेश लौटने से पूर्व भारतीय सेना ने वहां कुछ समय के लिए सत्ता संभाली थी। अब यह जगजाहिर तथ्य है कि श्रीलंका में भी भारतीय सेना ईपीआरएलएफ की रक्षा कर रही है, जबकि परोक्ष रूप से वह वहां की सरकार चला रही है।

एक अवकाशप्राप्त जनरल की मान्यता है कि ऐसे हालात सेना के नये जवानों के दिमाग में यह बात भर देते हैं कि यह उनकी ही ताकत है, जिसके दमखम पर नागरिक प्रशासन टिका रहता है। जब तक सेना के जवानों और अफसरों को लड़ाई के मकसद की समुचित जानकारी नहीं दी जाती और उनकी सेवाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक लड़ाई के दौरान वे अपनी सर्वोच्च ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते। मनोबल का गिरना तो तात्कालिक परिणाम होता है।

जनरल सुंदरजी : कैसे सेनाध्यक्ष थे ?

दिल्ली के साउथ ब्लाक में ही भारत के सेनाध्यक्ष का मुख्यालय है, जहां लगे दो अतिविकसित आईबीएम पीसी-एटी कंप्यूटर पलक झपकते ही भारतीय सेना से संबंधित हर प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं के इस शक्ति केंद्र में जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी १४वें सेनाध्यक्ष के रूप में एक फरवरी, १९८६ से दो वर्ष तीन मासों तक आसीन रहे। यद्यपि २१ मासों का यह समय बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन जनरल सुंदरजी भारतीय सेना को २१वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाने के कार्य में इस दौरान जुटे रहे। उन्होंने सेना के जवानों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनायी। उनके अफसर उन्हें 'आधुनिक दिमागवाले' सेना के 'यंत्रीकर्ता' और सोचनेवाले (थींकिग) जनरल के रूप में स्मरण करते हैं। उनके द्वारा भेजे गये टेलीग्राफिक संदेशों का तो नाम ही 'सुंदरग्राम' पड़ गया था। सेना को कंप्यूटरयुक्त आधुनिक साज सामानों से लैस करने की दिशा में सघन चर्चाओं के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री से जैसा तालमेल बिठाया था, उसे देखकर कहा जाता था कि तीनों एक दिमाग से सेना के आधुनिकीकरण के प्रति प्रयत्नशील हैं। कहा जाता है कि सेनाध्यक्ष का पद भार संभालने के पूर्व १५ दिनों तक गोवा के किसी अज्ञात स्थान में एकांतवास कर उन्होंने उन सारी बातों पर आत्ममंथन किया था, जिन्हें वे सेनाध्यक्ष के रूप में सरअंजाम देना चाहते थे। वे सेना के बख्तरबंद डिवीजनों के संस्थापकों में गिने जाते हैं और अपने वरिष्ठ सहयोगियों की नजर में वे एक बेहतरीन फौजी तथा श्रेष्ठ व्यूहरचनाकार माने जाते हैं। सत्तर के दशक मे वे उस तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे जो सेना के भावी स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिया करती है।

थल सेना के युद्धाभ्यास (जिसे आपरेशन ब्रासटेक्स का नाम दिया गया था) के दौरान उन पर यह संदेह किया गया था कि वे अरुण सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध के लिए उकसाना चाहते हैं, जिससे युद्ध हो और विजय का सारा यश व श्रेय उन्हें मिल सके। लेकिन अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इसका खंडन करते हुए कहा है, "यद्यपि यह सच है कि आपरेशन ब्रासटेक्स जनरल सुंदरजी के दिमाग की उपज था, लेकिन यह भी सच है कि उन दिनों भारत सरकार को भी संदेह था कि पंजाब के आतंकवादी उपद्रवों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान भी हमला कर सकता है।" दरअसल, राजनेता इस खतरे को वास्तविक मान रहे थे और सुंदरजी ने पाक सीमा पर ही व्यापक युद्धाभ्यास का आयोजन करके पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिये थे। इस युद्धाभ्यास से यह भी जगजाहिर हो गया था कि पंजाब की गड़बड़ियों के बावजूद भारतीय सेना हर हमले का मुकाबला करने में समर्थ है, भले ही यह हमला कितना ही बड़ा क्यों न हो।

बहरहाल, सेना में अफसरों का एक छोटा वर्ग ऐसा भी है जो जनरल सुंदरजी को पसंद नहीं करता, लेकिन सुंदरजी के एक प्रशंसक का कहना है, "सुंदरजी भविष्य के प्रति चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान सेना को अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित करने में लगाया, लेकिन अपने लोगों के लिए उन्हें बहुत थोड़ा वक्त मिला और इसी कारण वे जनसंपर्क में कमजोर रहे। दूसरी ओर, वे जहां अपने दिमाग से काम लेते थे, वहीं खुले दिमाग के भी थे और दो टूक बातें किया करते थे।"

बोफोर्स तोप सौदे की आलोचना के कुछ छींटे सुंदरजी पर भी पड़े हैं, क्योंकि उन पर भी आरोप है कि पहले वे फ्रांस की सोफमा तोपों को बेहतर बताते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी बोफोर्स तोपों के पक्ष में अपनी राय दे दी थी। सुंदरजी ने ऐसा क्यों किया ? इसका जवाब जनरल थामस देते हैं, "सुंदरजी को चेतावनी दी गयी थी कि पाकिस्तान के पास फायर-लोकेटिंग (गोला दागे जाने के ठिकाने की टोह लेनेवाला) राडार है और इससे बचने की क्षमता बोफोर्स तोपों में है। दूसरी बात यह थी कि फ्रांस के अपने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्वार्थ हैं जो युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ भी जा सकते हैं, जबकि स्वीडन की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में धन कमाने के सिवा अन्य कोई भूमिका नहीं है। तीसरी बात यह है कि फ्रैंच तोपों को ही हमेशा प्रोत्साहन मिलने से जनरल सुंदरजी थोड़ा चिंतित रहे होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में बोफोर्स तोप बहुत बेहतर नहीं, तो एक अच्छी तोप जरूर है। संभवत: इन्हीं कारणों से सुंदरजी ने स्वयं अपने विचार बदले हों, न कि किसी दबाव में। शायद यही वजह थी कि सुंदरजी ने मीडिया को दिये साक्षात्कार में बड़े दबंग तरीके से सारी बातों का खुलासा किया है।"

बहरहाल, बोफोर्स तोप सौदे को लेकर उठे विवाद में सरकार द्वारा सुंदरजी का हमेशा एक कवच के रूप में इस्तेमाल किया गया। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद में हुई बहस के दौरान भी सुंदरजी का नाम आया। कुछ सैन्य अधिकारियों का कहना है, "बड़ी चालाकी से संदेह की सुई सुंदरजी की ओर मोड़ दी गयी थी। यदि सुंदरजी सारी बातों का खुलासा नहीं करते, तो इसका सेना के मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सेनाध्यक्ष सेना के लिए एक श्रद्धेय-प्रतीक होता है, यदि उस पर अनैतिक होने का संदेह किया जाये, तो सेना का मनोबल कैसे कायम रखा जा सकता है ?" एक जनरल का कहना है, "उन पर गलती करने या देश की गोपनीय बातों को उजागर करने का आरोप लगाना नासमझी है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं, जब उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष या सरकार के प्रति निष्ठा रखने के बजाय राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय गौरव कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।" सेनाध्यक्ष तो पूरी सेना के गौरव का प्रतीक होता है। यदि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तो उसे सेना को भावी आलोचना से बचाने के लिए अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए और अनेक अफसरों का मानना है कि सुंदरजी ने यही किया है। एक सैन्य अधिकारी के अनुसार, "सेना के गौरव को बचाने के लिए उन्होंने जो जोखिम उठाया है, उसके लिए वे सदैव स्मरण किये जायेंगे।" खुद जनरल सुंदरजी का कहना है कि जान और आजादी के सिवा कोई उनसे और क्या छीन सकता है ?

जब शिक्षित होने के लिए भी
कर चुकाना पड़े-

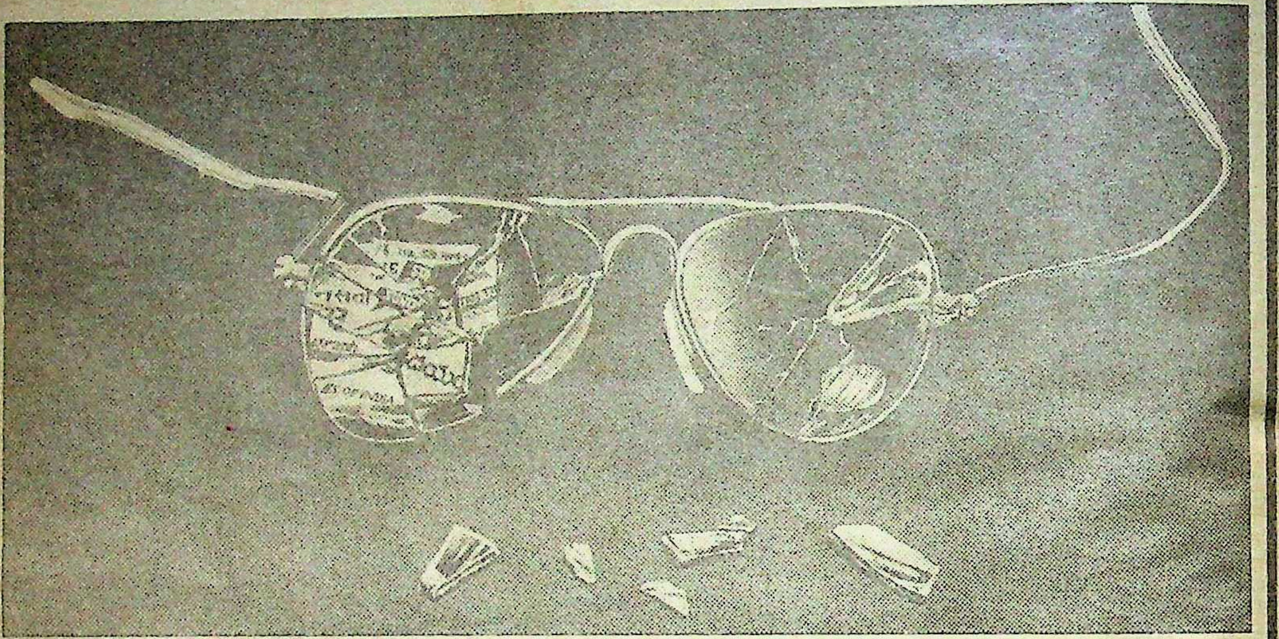

तो समझिये कि साक्षरता निश्चय ही
राष्ट्र-हित में नहीं.

यह तो "ज्ञान पर थोपा गया प्रतिबंध है और इसका सीधा-सादा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बोझ से लाद दिया जाए कि वह पढ़-लिख सकता है और अपने चारों ओर की दुनिया की जानकारी रखने के लिए अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सजग है."

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में यह कहा था और साथ ही उसने अखबारी कागज पर सरकार द्वारा लगाए गए 850 रुपए प्रति टन के आयात शुल्क को घटा कर 550 रुपए प्रति टन करने का फैसला भी दिया था.

अखबारी कागज की सरकारी मिलों ने अखबारी कागज की कीमत 40% तक बढ़ा दी है. विदेशी अखबारी कागज पर शुल्क फिर बढ़ा दिया गया है. छोटे और मझोले अखबारों को कुछ राहत जरूर दिखाई पड़ती दी गई हो लेकिन ज्यादातर अखबार जो 90% से भी ज्यादा अखबारी कागज का इस्तेमाल करते हैं, उन पर बोझ और ज्यादा ही बढ़ गया है.

परिणाम एकदम स्पष्ट है— लागत में वृद्धि, प्रकाशनों की कीमत में वृद्धि, विज्ञापन दरों में वृद्धि, अखबार उद्योग पर कमरतोड़ वित्तीय दबाव. यह दबाव प्रगति की रफ्तार को मंद करता है, कोने-कोने से खबरें लाने और कोने-कोने तक उन्हें पहुंचाने के काम में बाधा पहुंचाता है. पढ़ा-लिखा होना बेशक अब बड़ा बोझ बनता जा रहा है.

लोकतंत्र के नागरिकों को मुक्त ज्ञान, सूचना, बौद्धिक स्फूर्ति और मनोरंजन पाने का अधिकार है. इसके लिए प्रेस ही उनका एकमात्र स्वतंत्र और सस्ता स्रोत है. प्रेस लोकतंत्र की जान है, राजनैतिक और सामाजिक संवाद का प्राण तत्व है. भारत जैसे विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं वाले देश में अखबार ही इस महत्वपूर्ण विविधता के आइने होते हैं. यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, जन-मन की आवाज है, दबी-घुटी भावनाओं के लिए सेफ्टी वाल्व है लेकिन अखबार यह सब तभी तक कर सकते हैं जब तक उन पर सरकारी अंकुश न हो, उनकी आवाज दबाई न जाए.

सरकार ने अखबारों पर तो भारी वित्तीय दबाव डाल दिया है जबकि सरकारी प्रचार माध्यमों के विस्तार के लिए थैलियां खोल दी गई हैं.

इन सबकी भारी कीमत चुकानी होगी. और यह कीमत अंततः केवल अखबार उद्योग ही नहीं चुकाएगा. खतरे में पड़ेगी देश की लोकतांत्रिक चेतना, डूबेंगे राष्ट्र निर्माताओं के आदर्श. और यह कीमत जनता को चुकानी होगी.

राष्ट्र को नुकसान से सरकार का भला नहीं हो सकता .

राष्ट्र के हित में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी द्वारा जारी

MILESTONES/INS/342a Hin

सुंदरजी प्रकरण : सुंदरजी के मामले को ही लें। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो सुंदरजी के वक्तव्य पर संयमित प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन सुरक्षा मंत्रालय ने उसका खंडन किया, जिसका लुब्बेलुआब यही था कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जनरलों से अधिक सरकार की है। यह बात दूसरी है कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तोप सौदे के मामले में नौकरशाहों और राजनेताओं ने ही प्रमुख भूमिका निभायी और इसमें जो भी खामियां रह गयीं, उनकी वजह राजनेता रहे और वे ही सारे बवाल की जड़ हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय के खंडन से यह सवाल उठता है कि यदि सेनाध्यक्ष देश पर मंडरा रहे खतरे और सेना की उपयुक्त तैयारी के संबंध में समुचित आकलन करने में पूर्ण सक्षम नहीं हैं, तो सरकार किस आधार पर तय करेगी कि देश के सामने कैसा संकट खड़ा है और सेना को किस सीमा तक हथियारों एवं अन्य साज-सामान से सज्जित करना है।

फिलहाल, इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि सरकार अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष सुंदरजी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करेगी, लेकिन वेंगलराव एवं अन्य राजनेता जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, उनसे आम जनता के मन में यह शंका घर करती जा रही है कि सरकार पिछले दरवाजे से जनरल सुंदरजी को आतंकित करना चाहती है। रक्षामंत्री केसी पंत ने यह तो कहा है कि सुंदरजी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि भविष्य में भी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इससे संदेह को बल मिला है कि सरकार चाहती है कि सुंदरजी के सिर पर भय की तलवार हमेशा लटकी रहे।

ऐसे हालात से यह धारणा बनती है कि सेना के जनरल, राजनेता और नौकरशाह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि राजनीतिक नेतृत्व उचित-अनुचित का विचार करके सावधानी बरतेगा कि सुरक्षा सेनाओं को किसी ऐसे विवाद में न घसीटा जाये जो सेना का मनोबल गिराये। समझा जाता है कि सेना के अनेक अफसरों ने कांग्रेस सांसद केएन सिंह के इस वक्तव्य को पसंद नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आस्ट्रियन तोपों के बारे में अनुकूल रिपोर्ट देने के एवज में यदि कोई उनकी मुट्ठी गर्म करने को तत्पर था, तो जनरल हृदय कौल को चूकना नहीं चाहिए था। कम-से-कम सर्वज्ञ होने का दावा करनेवाले राजनेताओं को राष्ट्रहित में अपना मुंह बंद रखना चाहिए—जिन्हें सेना के कामकाज की रत्तीभर जानकारी नहीं है।

एक अवकाशप्राप्त सुरक्षा सचिव के जरिए से आयी यह रिपोर्ट भी व्यग्र करनेवाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्ता द्वारा जनरल सुंदरजी का इस्तेमाल करने और फिर उनकी सार्वजनिक आलोचना करने से कुछ अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारी खुश नहीं हैं। सवाल उठता है कि बोफोर्स तोप सौदे के बचाव में राष्ट्र से क्या कीमत मांगी जा रही है? क्या राष्ट्र इसके बचाव के एवज में सेना में राजनीतिकरण का बीज वपन करने का जोखिम उठा सकता है?

—आरके मिश्र

भारत के सेनाध्यक्ष

१. मार्शल केएम करियप्पा
२. जनरल राजेंद्र सिंह
३. जनरल श्रीनागेश
४. जनरल केएस थिमैया
५. जनरल पीएन थापर
६. जनरल जेएन चौधरी
७. जनरल पीपी कुमारमंगलम
८. फील्ड मार्शल एस मानेक शा
९. जनरल जीजी बेवूर
१०. जनरल पीएन रैना
११. जनरल ओपी मल्होत्रा
१२. जनरल केवी कृष्णराव
१३. जनरल एएस वैद्य
१४. जनरल सुंदरजी
१५. जनरल वीएन शर्मा

Mastaba
2 in one
Mastaba
2 in one

ना कम ना ज्यादा,
सम्पूर्ण स्वाद का वादा

सही वजन - उत्तम क्वालिटी
पान मसाला और तम्बाकू का सम्पूर्ण मिश्रण

मस्ताबा
टू इन वन

5 ग्राम

मार्केटिंग एजेंट: **धर्मपाल सत्यपाल**
बी 18, सैक्टर 3, नौएडा, गाजियाबाद (यू०पी०)

BUSS/DEL

वैधानिक चेतावनी—तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अजेय सिंह की संपत्ति कितनी जायज ?

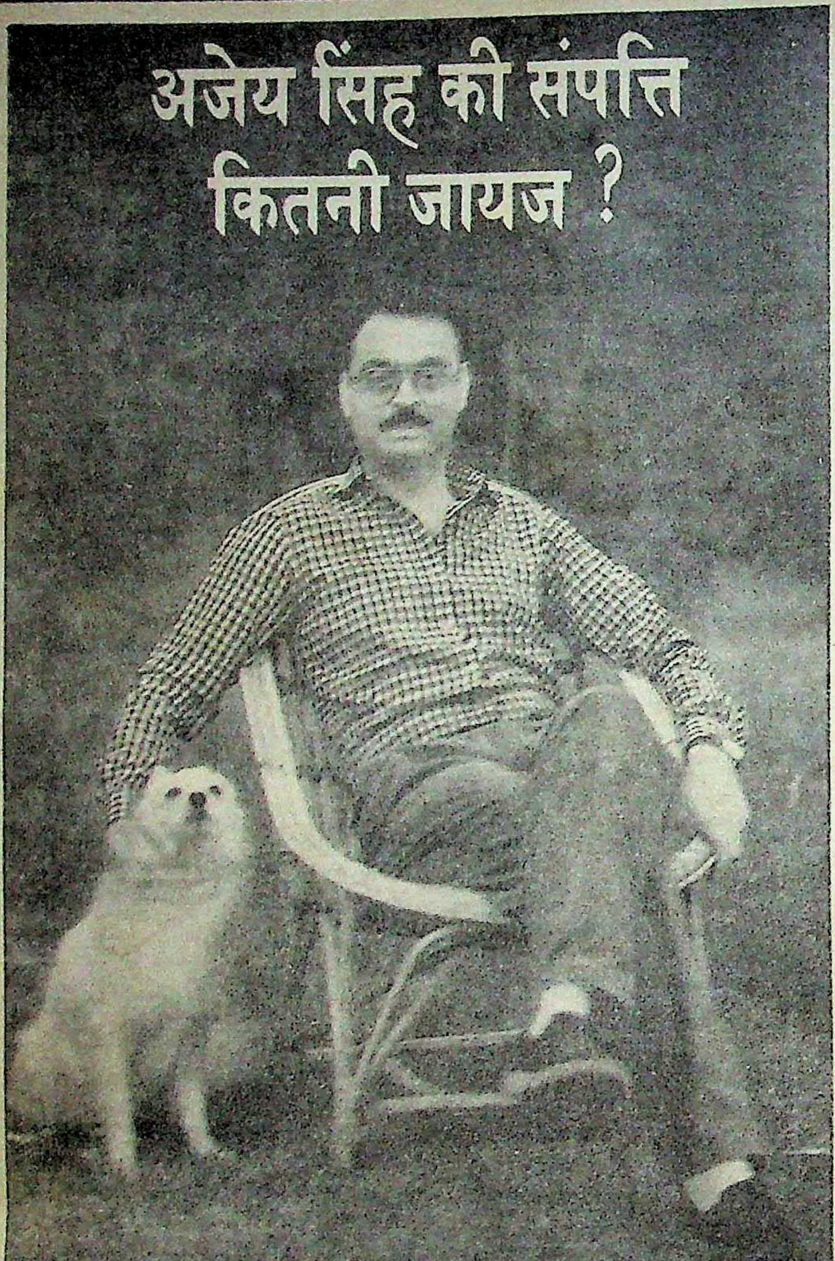

छाया : सुनील सक्सेना

कांग्रेस के कतिपय बड़बोले नेताओं और समाचार पत्रों ने वीपी सिंह के पुत्र अजेय सिंह पर भ्रष्ट तरीके से सेंट किट्स बैंक में धन जमा करने का आरोप धमाकेदार ढंग से उछाला। लेकिन जब अजेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा ठोंकने की धमकी देते हुए उन्हें आरोप सिद्ध करने की चुनौती दी, तो सबने एकबारगी चुप्पी साध ली। क्या वे सबूत जुटाकर अपनी चुप्पी तोड़ पायेंगे ?

विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुत्र अजेय सिंह द्वारा जनता को अपनी आय और सम्पत्ति का ब्यौरा दिये जाने के पश्चात प्रवर्तन निदेशक ने अचानक चुप्पी क्यों साध ली ? क्या ये सरकारी अधिकारी अपने विरुद्ध अजेय सिंह की अदालती कार्रवाई करने की धमकी से डर गये हैं ? क्या कारण है कि फिर से कल्पनाथ रायों, केके तिवारियों, डा० एनकेपी साल्वों ने अपने मुंह बंद कर लिये ? चाहे जो भी हो, उन्हें वीपी सिंह के खिलाफ हुड़दंग मचाते रहना चाहिए था ! क्या कारण है कि युवा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को यह सलाह दी कि उसे अजेय सिंह की सम्पत्ति का पता लगाने के लिए अमरीकी सरकार की मदद लेनी चाहिए ?

क्या इसका कारण यह है कि इन सबने यह मान लिया है कि अजेय सिंह के खिलाफ लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं किया जा सकता ? सेंट किट्स के जिस बैंक में अजेय सिंह पर धन जमा करने का आरोप है, उस बैंक के पूर्व प्रधान जार्ज मैक्लिन हालांकि अभी भी खामोश नहीं हुए हैं। अजेय सिंह ने आरोप लगाया था कि फर्जी दस्तावेजों के द्वारा कुछ समाचारपत्रों ने उन्हें लांछित किया है। इसी सिलसिले में जार्ज मैक्लिन ने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, वह हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि बेतुका भी है।

मैक्लिन का झूठ : अजेय सिंह का कहना है कि दस्तावेज में दिखायी गयी ब्याज की गणना गलत की गयी है और कोई भी बैंक इतनी भयंकर भूल नहीं कर सकता। इस विवाद में मैक्लिन ने स्वीकार किया है कि यह गणना उन्होंने खुद ही की थी और ऐसा लगता है कि इसमें किसी कैल्कुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संभवत: इसी कारण ब्याज की गणना में इतनी सारी गलतियां हुई। लेकिन मैक्लिन को अधिक होशियारी से काम लेना चाहिए था। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उनके बैंक के किसी क्लर्क ने इस तरह की भयंकर भूलें की होतीं, तो मैक्लिन ने छूटते ही अपने मातहत उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया होता। इसके अलावा उन्हें यह पता होना चाहिए था कि अपने हाथों की गयी गणना के उनके दावे की इस दंतकथा पर केवल नादान लोग ही यकीन कर सकते हैं। यह बात सर्वविदित है कि अमरीका में सातवीं कक्षा के बच्चे भी अपने जेब में कैल्कुलेटर रखा करते हैं। वास्तव में वहां के बहुत से बच्चे स्वयं हिसाब-किताब नहीं करते, क्योंकि इसकी वहां कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल, मैक्लिन ने स्वयं को रहस्यमय व्यक्ति बना लिया है। किसी बैंक का प्रमुख भला अपने ग्राहक के दुश्मनों की सहायता करने के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा ? किसी भी बैंकर ने ऐसा कभी नहीं किया। फिर भला एक बैंकर सार्वजनिक रूप से यह कैसे कह सकता है कि ब्याज की गणना करने में उसने खुद ही गलती की है ? इस पर तुर्रा यह है कि इस गलती के लिए वे 'माफी' मांगने को भी

तैयार नहीं हैं। मैक्लिन ने इस रहस्य को एक और तरह से भी बढ़ा दिया है। दिल्ली में जो भी उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहते थे, उनमें से किसी को भी मैक्लिन ने टेलिफोन पर संपर्क करने की इजाजत नहीं दी। कइयों ने बेहद कोशिश की, लेकिन मैक्लिन नहीं मिले। दूसरी तरफ, कुछ समाचारपत्रों ने मैक्लिन से बात की और कुछ ही घंटों में उनका बयान भी हासिल कर लिया। लेकिन ये बयान ऐसे हैं, जिनसे अजेय सिंह के शत्रुओं को ही मदद मिलती है। प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जार्ज मैक्लिन कोई जीते-जागते बैंक मुख्याधिकारी हैं या उनकी जगह कोई और ही यह सब लिखता रहा और बयान देता रहा है? सरकार ही यदि चाहे तो इस भेद का पता लगा सकती है।

बहरहाल, यह सब जानकारी किसी भी तरह यह बात साबित नहीं करती कि अजेय सिंह ने भ्रष्ट तरीके से धन नहीं कमाया। अजेय सिंह का दावा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और यहां तक कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशक को भी यह धमकी दी कि यदि मैक्लिन के दस्तावेजों के आधार पर (जिन्हें अजेय सिंह फर्जी बताते हैं) उन पर और अधिक लांछन लगाया गया, तो वे प्रवर्तन निदेशक पर अदालत में मुकदमा चलायेंगे। फर्जी दस्तावेज गढ़ना या किसी पर लांछन लगाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है अजेय सिंह के खिलाफ कोई जालसाजी नहीं हुई है, यह साबित करना तो सरकार और सत्ताधारी दल का फर्ज है। इसके साथ उन समाचारपत्रों का भी यह दायित्व है, जिन्होंने दस्तावेज की फोटो-प्रति छापी थी।

संपत्ति का ब्यौरा: जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी अजेय सिंह की संपत्ति को देखकर ही अपनी राय कायम कर सकता है। अपने बैंक के जमाखातों, कंपनी शेयरों और जायदाद के ब्यौरों में उन्होंने बताया है कि उनकी कुल सम्पत्ति १, २६, ७०० अमरीकी डालर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंदन स्थित अपने एक मकान का भी जिक्र किया है, जिसकी कीमत ५७००० डालर है।

इस मकान के लिए उन्होंने ऋण लिया है, उसकी अदायगी ब्याज समेत २५ वर्षों में की जानी है। अतः जिस चीज के वे वास्तविक स्वामी हैं, उसे अर्जित संपत्ति फिलहाल नहीं माना जा सकता। शेयरों का मूल्य वही दर्शाया गया है जिस मूल्य पर उन्होंने इन्हें खरीदा था। कुछ मामलों में उनके पास खरीदे गये शेयरों से अधिक शेयर हैं, क्योंकि इन्हें उन्होंने बोनस के रूप में हासिल किया था। चूंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बोनस के रूप में उन्होंने कितने शेयर प्राप्त किये, अतः यह बात तार्किक दृष्टि से आश्वस्त होकर कही ज. सकती है कि उनके पास कुल जितने शेयर हैं, उनका एक तिहाई भाग उन्होंने बोनस के रूप में प्राप्त किया होगा। इस पूर्वानुमान के अनुसार उन्होंने सारा धन जो शेयरों में लगाया और बैंकों में जमा कराया, वह १,२६,७०० डालर है।

रुपए की मुद्रा में यह धनराशि कितनी होती है? २१ लाख चालीस हजार रुपए से कुछ ज्यादा। यह एक बड़ी रकम दिखती है, लेकिन यहां यह याद रखना होगा कि ऐसा डालर के वर्तमान विनिमय मूल्य के कारण है। दस साल पहले इतने ही डालर का विनिमय मूल्य दस लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा ही होता।

क्या अजेय सिंह अपनी नियमित आय से इतनी रकम बचा सकते थे? यदि बचा सकते थे, तब तो भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अजेय सिंह ने अपने अगस्त, १९८९ के वर्तमान वेतन के बारे में ही बताया है। इसके पूर्व उन्हें कितना वेतन मिलता था, इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। अतः यहां पर भी उचित पूर्वानुमान पर ही भरोसा किया जा सकता है। जहां तक संभव हो यह पूर्वानुमान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि वह विश्वसनीय बन सके। अमरीका में सिंह जैसे योग्य और अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए ५५,००० डालर का सालाना वेतन बहुत ज्यादा नहीं समझा जाता। करीब १२ वर्षों से वे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्य करते रहे हैं, अतः यह अनुमान लगाना कि पिछले वर्षों में उनकी आय वर्तमान आय से बहुत कम रही होगी, उचित नहीं है। उनका न्यूनतम वेतन कभी ४२ हजार डालर से कम नहीं रहा होगा।

> जो लोग इस दावे पर उंगली उठाते हैं, उन्हें या तो किये गये पूर्वानुमान को गलत साबित करना पड़ेगा या यह साबित करना पड़ेगा कि जितना खर्च यहां बताया गया है, अजेय सिंह हकीकत में उससे कहीं अधिक खर्च करते हैं। इसके अलावा इस प्रसंग में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों का संदेह भी नहीं हो सकता, बशर्ते कि अजेय सिंह द्वारा अपनी अर्जित संपत्ति का ब्यौरा सही दिया गया हो।

बचत का अनुमान: इस आय से कितनी बचत संभव है? यह बात परिवार के आकार, चीजों के दामों और रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करती है। यदि अजेय सिंह ने अमरीकियों अथवा अंग्रेजों जैसा विलासितापूर्ण जीवन न बिताया होता और यदि उनके परिवार में दो से अधिक सदस्य न होते (केवल वे और उनकी पत्नी ही अमरीका में रहते थे और पता चला है कि उनकी एक मात्र युवा पुत्री कलकत्ता में अपनी दादी के पास रहती हैं) तब इतनी बचत करना काफी हद तक संभव है।

वास्तव में, ऐसा लगता है कि अजेय सिंह इससे भी ज्यादा बचा सकते थे। अमरीका में आवासीय व्यय और चिकित्सा खर्च सर्वाधिक मंहगे होते हैं। परंतु न्यूयार्क के एक अच्छे इलाके में दो कमरों के फ्लैट का किराया अभी भी १५०० से १८०० डालर से कम नहीं है। १९७८ या १९७९ में यह किराया लगभग इसका एक-तिहाई था। बाकी खर्च के लिए आजकल भी एक माह में प्रति व्यक्ति ५०० डालर एक भारतीय के लिए काफी अच्छी रकम होती है।

इसका मतलब यह हुआ कि १९८९ में प्रति व्यक्ति १५०० डालरों का मासिक व्यय काफी है। इस तरह पति-पत्नी ३६ हजार डालर में साल भर मजे से रह सकते हैं और ५५,००० डालर में से साल भर में १९,००० डालर बचा सकते हैं। पहले वेतन शायद कम था, लेकिन उसी प्रकार महंगाई कम रहने से खर्च भी कम था। अतः कर कटौती के बावजूद अजेय सिंह की बचत उससे काफी अधिक हो सकती थी, जितना कि वे बचा पाये।

११ वर्षों में १, २९, ७०० डालर जमा करने के लिए प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत की ब्याज दर पर किसी व्यक्ति को कितनी बचत करनी पड़ेगी? यदि कोई प्रतिवर्ष ७,००० डालर चार वर्ष तक जमा करता है, तो उसे ३३,२५० डालर मिलते हैं और यदि कोई अगले ७ साल तक प्रतिवर्ष १०,००० डालर जमा करता है, तो उसे ९२, ५९८ डालर मिलते है। इन दोनों को मिलाकर कुल १,२५,८४८ डालर की बचत होती है। अतः १, २९, ७०० डालर की बचत करने के लिए पहले ४ या अगले ७ सालों में थोड़े ही डालर और जमा करने होते। इस प्रकार अजेय सिंह बैंक में इससे भी अधिक पैसा जमा कर सकते थे, यदि वास्तव में उनकी न्यूनतम और अधिकतम आय उतनी ही होती, जो ऊपर बतायी गयी है। जो लोग इस दावे पर उंगली उठाते हैं, उन्हें या तो ऊपर किये गये पूर्वानुमान को गलत साबित करना पड़ेगा या यह साबित करना पड़ेगा कि जितना खर्च यहां बताया गया है, अजेय सिंह हकीकत में उससे कहीं अधिक खर्च करते रहे हैं। इसके अलावा इस प्रसंग में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों का संदेह भी नहीं हो सकता, बशर्ते कि अजेय सिंह द्वारा अपनी अर्जित संपत्ति का ब्यौरा सही दिया गया हो।

—कुमारेश चक्रवर्ती

एच डी एफ़ सी वैयक्तिक
गृह ऋण

अपना घर पाने का सब से जल्द और आसान उपाय

- निवास-स्थान के लिए
- ऋण की रकम भुगतान क्षमता के अनुसार
- अधिकतम ऋण 2.5 लाख रु. तक
- भुगतान मासिक किस्तों में 20 वर्ष तक
- ब्याज दर प्रतिवर्ष 12.5% से 14.5% के बीच
- विशेष विकल्प जैसे शॉर्ट-टर्म ब्रिजिंग ऋण सुविधा, टेलिस्कोपिक ऋण योजना और स्टेप-अप भुगतान सुविधा.

हमारी किसी भी शाखा में चले आएं या यह कूपन आज ही डाक से भेज दें.

एच डी एफ़ सी समझते हैं कि आप अपने नए घर में जल्दी-से-जल्दी पहुंचना चाहते हैं. हमारी आसान ऋण प्रक्रियाएं इस बात का भरोसा हैं, कि आप का ऋण जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो.

हमारी सुविधाएं आपकी विशेष जरूरतों के अनुसार हैं. अगर आप चाहें तो हमारे कर्मचारी खुशी से आपकी मदद करेंगे. आपकी घर की जरूरतों के लिए हम व्यापक योजना पेश करते हैं. साथ ही देश-भर में फैला सेवा जाल जो यह लाभ आपके दरवाजे तक ले आता है.

कृपया मुझे एच डी एफ़ सी वैयक्तिक गृह ऋण पुस्तिका की एक मुफ्त प्रति भेजें.

नाम : ____________________

____

पता : ____________________

____

____

Code: L/MY

यहां भेजें :

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

कोहली हाउस, 4-ई, रामतीर्थ मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 394. लखनऊ 226 001. फ़ोन : 35055, 47505.

एच • डी • एफ़ • सी

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस : बम्बई.

शाखाएं : अहमदाबाद • बंगलूर • भुवनेश्वर • बम्बई (परेल) • कलकत्ता • चंडीगढ़ • कोचीन • कोइम्बतूर • गुवाहाटी • हैदराबाद • इंदौर • जयपुर • लखनऊ • मद्रास • नई दिल्ली • पुणे • त्रिवेंद्रम • वडोदरा • वाशी (न्यू बाम्बे)

ULKA-12582-H-IHL-89-HIN

चूहों की वंशवृद्धि

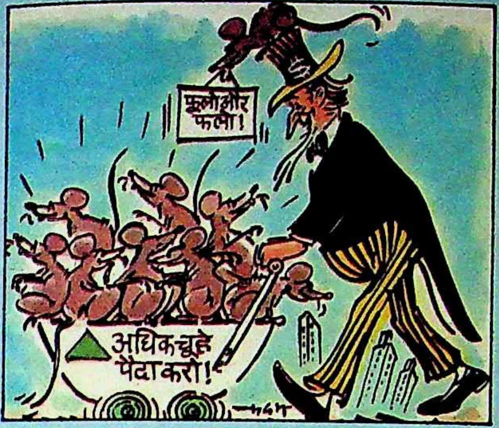
फूलो और फलो!
अधिक चूहे पैदा करो!

धार्मिक दृष्टि से चाहे भले हम गणेश के वाहन के रूप में चूहे की पूजा कर लें, लेकिन सच तो यही है कि तीसरी दुनिया के तमाम मुल्क चूहों से होनेवाली बरबादी से परेशान हैं। वे उनके उन्मूलन पर अकूत धन खर्च कर रहे हैं। लेकिन अमरीका इतना चूहाप्रेमी हो गया है कि वह निरंतर उनकी संवृद्धि की कोशिश में लगा है। दरअसल औषध विज्ञान का प्राय: हर प्रयोग पहले चूहों पर होता है। चूंकि वहां चूहों की कमी हो गयी है, इसलिए अमरीका चिंता में दुबला हुआ जा रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका की मेन स्थित शोधशाला, जोकि चूहों के वितरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, चूहों की पैदावार बढ़ाने के लिए सब कुछ करने में लगी है।

१३३ साल का दूल्हा

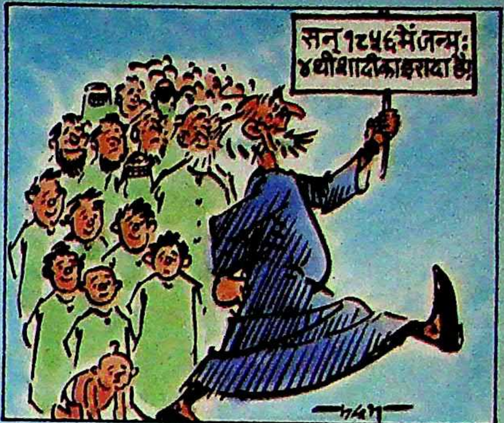
सन् १८५६ में जन्म: ४थी शादी का इरादा है

आज के जमाने में कोई सौ साल तक खुशी-खुशी जी ले, यही बड़ी बात है, लेकिन ईरान के अरक नामक शहर से सटे एक छोटे से गांव के कृषक निजामअली वरमज्यार इसकी एक जिंदा मिसाल हैं। फिलवक्त उनकी उम्र १३३ साल है। यह तो उनका रेकार्ड है ही, असली रेकार्ड तो वे अब कायम करने जा रहे हैं, इस उम्र में चौथी शादी करके। दरअसल अब से ४० साल पहले उनकी तीसरी बीवी गुजर गयी थी, तब से बेचारे अकेले ही जिंदगी काट रहे थे। वैसे वे ६ लड़कों के बाप और ६५ पोतों के दादा हैं और परपोते तो उनके अनेक हैं। उनका सबसे बड़ा लड़का ८५ साल का होकर मरा और सबसे छोटा लड़का ५० साल का है।

चर्च के चोर

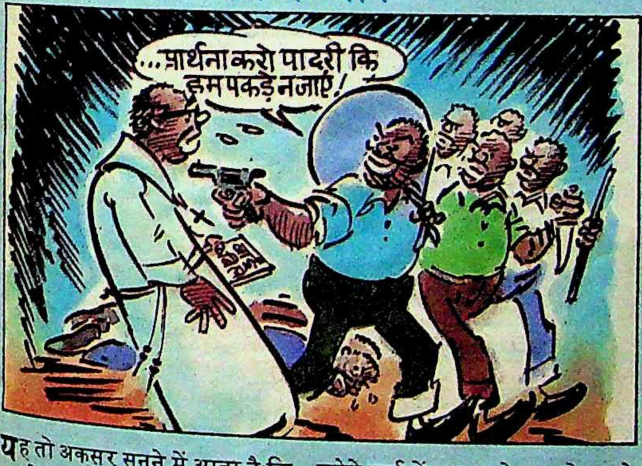
...प्रार्थना करो पादरी कि हम पकड़े न जाएं!

यह तो अकसर सुनने में आता है कि चोर जब चोरी करने जाते हैं, तब वे देवी-देवताओं की मनौती मान कर जाते हैं। लेकिन अफ्रीका में एक ऐसी घटना घटी, जिसमें लुटेरों ने चर्च के पादरी सहित भक्तों को लूटा और धमकाया भी कि जब तक वे बाहर न निकल जायें, तब तक वे उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे।

'डेली स्केच' समाचार पत्र के हवाले से बताया गया है कि नाइजीरिया की राजधानी के पास इकोरोडू में रविवार के दिन सुबह प्रार्थना के समय पांच हथियारबंद लुटेरे चर्च में घुस आये। उनके घुसते ही वहां हड़कंप मच गया। उनमें से दो लुटेरों ने भक्तों का सामान छीनना शुरू कर दिया और दो चर्च के कीमती सामान उठाने में लग गये। चर्च में रखे वाद्ययंत्रों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वे इतने बद्तमीज थे कि लूटने के बाद वेदी की ओर जाने से पूर्व उन्होंने सभी को मुंह नीचे कर जमीन पर लेट जाने का आदेश दिया और वहां जाकर बीयर पी। यही नहीं पीने के बाद उन्होंने पादरी से कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वे पकड़े न जायें।

छिपकलीभोजी

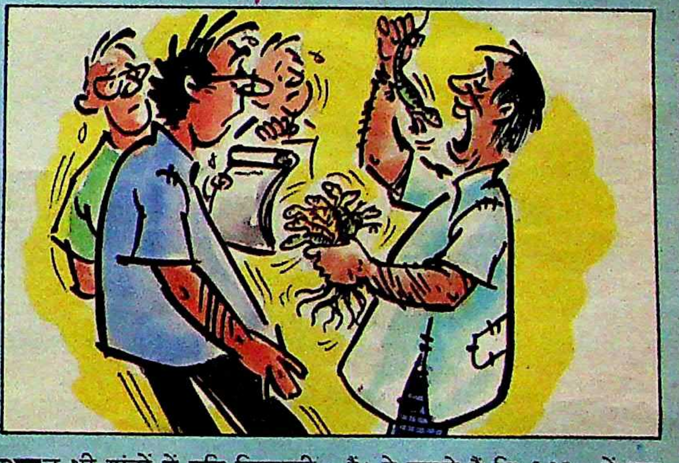

आज भी गांवों में यदि छिपकली शरीर पर गिर जाये, तो लोग अपशकुन मानते हैं तथा नहा-धोकर दान-दक्षिणा देते हैं। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे देख भर लेने से घिघियाने लगते हैं और अनेक औरतों को 'फोबिया' हो जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि एक छिपकली रोजाना खाता हो, तो किसे आश्चर्य नहीं होगा! लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया, अहमदाबाद के मुलाजिम नरनभाई को कुछ ऐसा ही शौक है। वे पिछले दो दशकों से प्रतिदिन एक छिपकली भोजन में लेते हैं। वे बताते हैं कि १९६८ में एक बार वे अनजाने में खाने के साथ एक छिपकली खा गये। उन्हें पता तब चला, जब खाना खतम करते-करते उसकी पूंछ उनके हाथ में रह गयी। लेकिन खाने के बाद उनको जोरों की नींद आयी। तब से गहरी नींद के लिए वे अकसर छिपकली खाने लगे। जब संवाददाताओं ने उनके रोजाना छिपकली खाने पर संदेह व्यक्त किया, तो उन्होंने एक ही बैठक में तकरीबन दस छिपकलियां खाकर दिखा दीं।

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शाम उतर आयी थी। अपने भारी-भरकम कर्घे पर खूबसूरत कालीन बुनती अब्दुल्ला की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। डिज़ाइनदार कालीन में आखिरी टांका लगाते हुए अचानक उन्हें सन् १९७७ की याद हो आयी...जब शाहजहांपुर के कालीन बुनकर बेतरह खस्ताहाल थे। विरासत में प्राप्त हुनर लुप्त हो चला था। उनका सारा उत्साह ही टूट चुका था। उन दिनों ऊनी कालीन का न कोई कद्रदान था, न बाज़ार। तभी आई टी सी त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से उनकी मददगार बनी।

शाहजहांपुर के अब्दुल्ला। इनके हाथों का हुनर इन्हें दो वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा था।

तभी आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के माध्यम से उनकी बुनी कालीनों के निर्यात द्वारा उनकी प्रतिभा को पुनर्जीवित किया।

निर्यात एजेंसी के रूप में, आई टी सी विदेशी खरीददारों की ज़रूरतों के अनुकूल।

इस प्राचीन कला-कारीगरी को पुनर्जीवित करने के लिए आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स की स्थापना की। कर्नल प्रेम सहगल (आई एन ए ख्यातिप्राप्त) के नेतृत्व में त्रिवेणी ने २५०० से भी ज्यादा प्रतिभाशील लेकिन गरीब बुनकरों को मदद दी। सन् १९७७ में ४ रुपये प्रति वर्ग फीट मजदूरी बढ़कर अब तो १५० रुपये हो चुकी है और क्वालिटी में भी खासा सुधार हुआ है। विदेशों को निर्यात किये जानेवाले कालीनों पर त्रिवेणी को करीब १ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का मुनाफा भी होने लगा है।

कालीनों के अलावा, आई टी सी का एक्सपोर्ट डिवीज़न दुनिया भर में अन्यान्य विविध सामग्रियों का निर्यात करता है। इन सामग्रियों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, समुद्री खाद्य, पोशाकें और अन्यान्य हस्तशिल्प भी शामिल हैं। इसके अलावा ताज़ा फल, सब्ज़ियां, मसाले और प्रोसेस्ड खाद्य भी निर्यात किये जाते हैं। आई टी सी नये-नये बाज़ारों का पता लगाकर बिक्री भी बढ़ा रही है। इस तरह आइ टी सी विदेशी मुद्रा की आमदनी में वृद्धि द्वारा देश को सहयोग दे रही है।

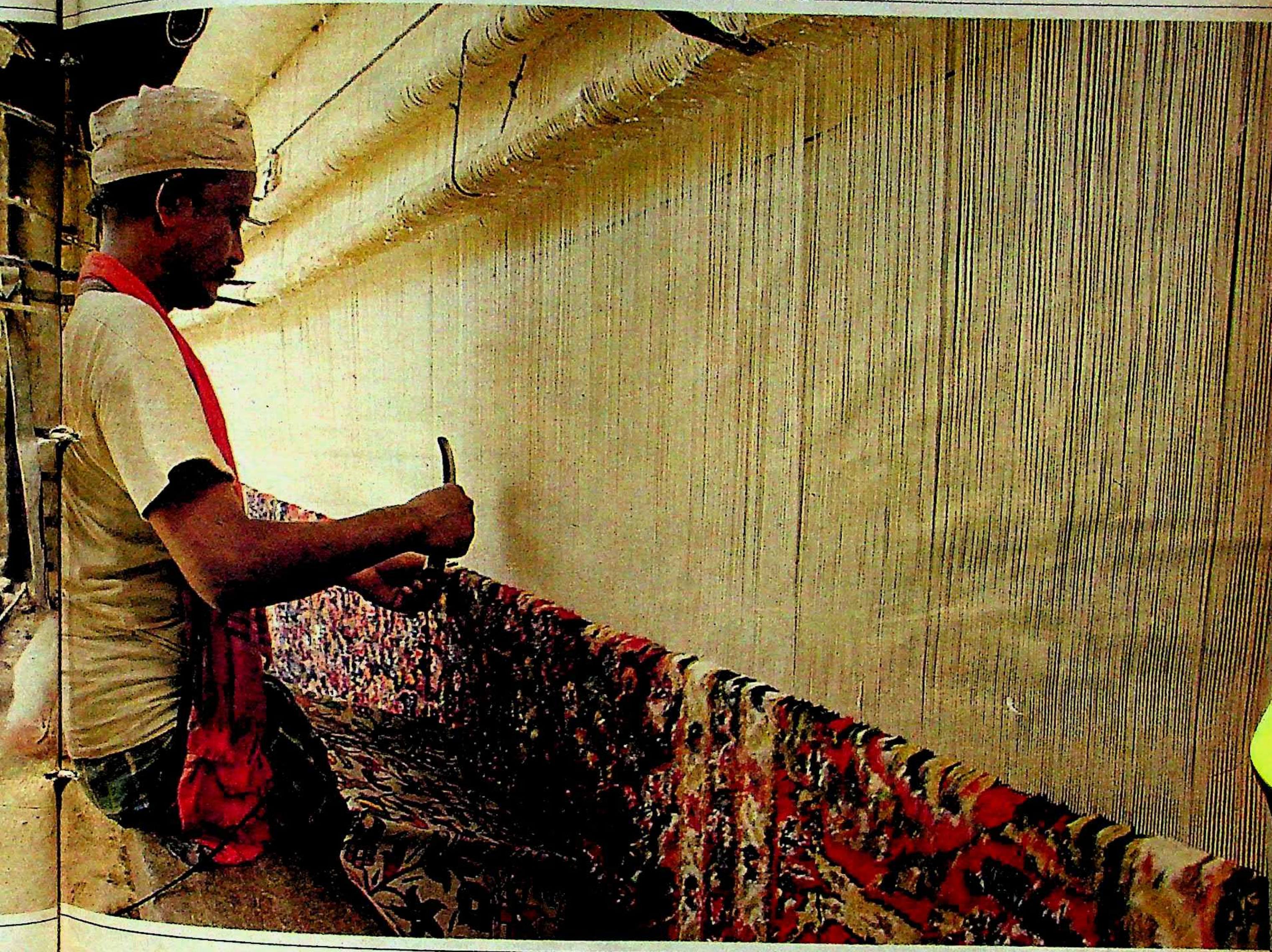

आई टी सी भारत के लिए और कहाँ-कहाँ कार्यरत है?

कृषि उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी। खाद्य-अखाद्य तेलों एवं सहायक उत्पादनों के निर्माण और मार्केटिंग के साथ-साथ, आई टी सी ने आयात भी कम किया है।

परिवार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी करोड़ों की संख्या में निरोध साधन वितरित कर रही है और छोटे परिवार एवं कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के लाभ का प्रचार-प्रसार कर रही है। इसके अथक प्रयासों को सन् १९८८ के एफ आई सी सी आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पेपर और बोर्ड — कोर सैक्टर में : आई टी सी द्वारा विकसित भद्राचलम पेपरबोर्ड्स अपने क्षेत्र में अग्रणी है। इसने रिकॉर्ड उत्पादकता के साथ साथ वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी कल्याण के प्रति गहरी जागरूकता का नया मानदंड स्थापित किया है।

I.T.C. Limited

Contract. ITC. 60.89 HIN

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

रीता भादुड़ी की पूछ

जिस रीता भादुड़ी को अभिनय-कौशल के बावजूद बड़े परदे पर कोई नहीं पूछ रहा था, वही रीता अब फिल्म-निर्माताओं के लिए क्रेज बन गयी हैं। क्योंकि छोटे परदे पर जितने सीरियलों में उन्होंने रोल किये, वे सभी सराहे गये। 'मुजरिम हाजिर' से तो निर्माता-निर्देशक उनके पीछे पड़े हुए हैं। कभी ऋषिकपूर ने उन्हें 'जहरीला इंसान' से निकलवाकर दम लिया था, लेकिन वही ऋषि उनसे माफी मांगते हुए साथ-साथ फिल्में करने का आफर भेज रहे हैं तथा उनसे टीवी छोड़कर बड़े परदे पर अपना करिश्मा दिखलाने की सलाह दे रहे हैं। रीता की भी जर्रानवाजी देखिए कि सब कुछ जानते-बूझते वे कहती हैं, "यह सब तो होता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं दक्षिण और गुजराती फिल्मों में सुपरस्टार कैसे बन पायी होती? रही बात टीवी पर काम करने की, तो परदा-तो परदा ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा।"

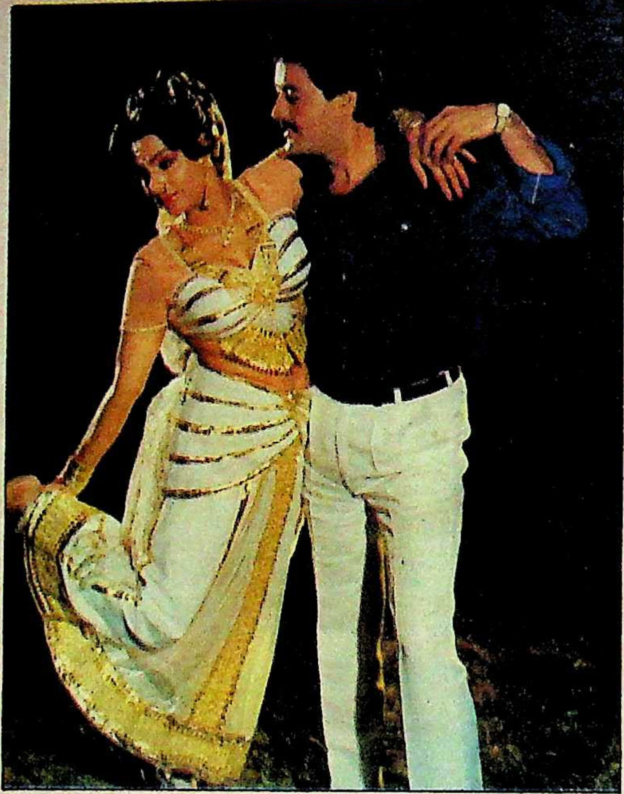

पद्मा खन्ना और अभिषेक 'कजरी' में

छाया: धर्म मूलचंदानी

कैकेयी का नूर

जब पद्मा खन्ना के समय की खलनायिकाएं बढ़ती उम्र के कारण दादियों-नानियों सरीखी दीखने लगी हैं, तब बूढ़ी कैकेयी की भूमिका निभानेवाली पद्मा के चेहरे पर नूर बरसने लगा है। खलनायकों की भीड़ से ठसाठस तथा खलनायिकाओं से वीरान फिल्म इंडस्ट्रीवालों को पद्मा के इस नूर ने कुछ ऐसा बेहाल किया है कि वे उन्हें साइन करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे हैं। लेकिन वक्त की मार और बंबइया फिल्मकारों के रवैये से पूरी तरह वाकिफ पद्मा सिर्फ वे ही फिल्में चुन रही हैं, जो उन्हें हेलन नहीं कुलदीप कौर बनायें।

अब सोनम से लेकर माला सिन्हा तक उम्र से आधी लगने का राज जानने के लिए रेखा के बजाय पद्मा खन्ना का दरवाजा खटखटा सकती हैं!

विनोद मेहरा और जयाप्रदा 'शाहजादे' में

जयाप्रदा : पुराना फार्मूला

पिटती फिल्मों और श्रीदेवी की साख ने जयाप्रदा को कुछ इस कदर बौखलाया कि उन्होंने श्रीदेवी तथा रेखा की स्टाइल में रिवाल्वर रानी जैसी भूमिकाएं करना शुरू कर दिया है। उनके हमदर्दों ने उन्हें लाख समझाया कि बंदूक क्या तोप चला लो, श्रीदेवी से लेकर वैजयंती माला तक की नकल कर लो, लेकिन रहोगी तो जयाप्रदा ही। अब पता नहीं उन्हें यह बात समझ में आयी या नहीं, लेकिन ऐन संकट के क्षणों में उनकी मदद के लिए आगे आ जानेवाले राज सिप्पी ने जरूर 'शाहजादे' में जयाप्रदा के लिए जयाप्रदा जैसी भूमिका गढ़ दी—अविवाहित मां की, जो अपने बेटे को उसके ही पिता से बदला लेने के लिए पाल-पोस कर बड़ा करती है। जयाप्रदा को इस फिल्म में कुछ ऐसा मजा आया कि उन्होंने सलीम की नयी फिल्म में बिना शर्त काम करने तथा 'फुलकोआपरेशन' की पेशकश कर दी, क्योंकि बिना नामवाली इस फिल्म के डायरेक्टर राज सिप्पी जो थे।

शब्बो की पहल

पत्रकारों के चेहरे से भी बिदकनेवाली शबाना आजमी उर्फ शब्बो ने पत्रकारों से संबंध सुधारने की पहल खुद शुरू कर दी है। टाइम्स आफ इंडिया के प्रकाशकों ने 'इंडियन पोस्ट' के पूर्व संपादक विनोद गुप्ता की बेदखली के अन्याय के प्रतिकारस्वरूप 'द इंडिपेंडेंट' का संपादक बनाकर उनके सहकर्मियों को भारी-भरकम पगार पर नियुक्त किया, तो शब्बो टाइम्स के अन्याय पीड़ित अन्य पत्रकारों को न्याय दिलाने का झंडा लेकर उनके साथ न केवल छह सितंबर को धरना में आ कर बैठ गयीं, बल्कि प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भी कीं और उन लोगों के बेबाक इंटरव्यू भी ले बैठीं, जिन्होंने बड़े फख्र से कभी उनके इंटरव्यू छापे थे। एक पत्रिका की कभी तथाकथित 'घोस्ट एडीटर' रह चुकीं शबाना का 'इनजस्टिस वर्सेज जस्टिस' मुद्दे पर लिया गया यह इंटरव्यू छपने के लिए नहीं, न्याय का रास्ता दिखलाने के लिए था।

अब गाशिप पत्रकार यह नहीं कह सकेंगे कि इस बार भी शब्बो सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए पत्रकारों के धरने की सदारत करने आयी थीं!

—अखबारी लाल

Har Safar Main HumSafar....

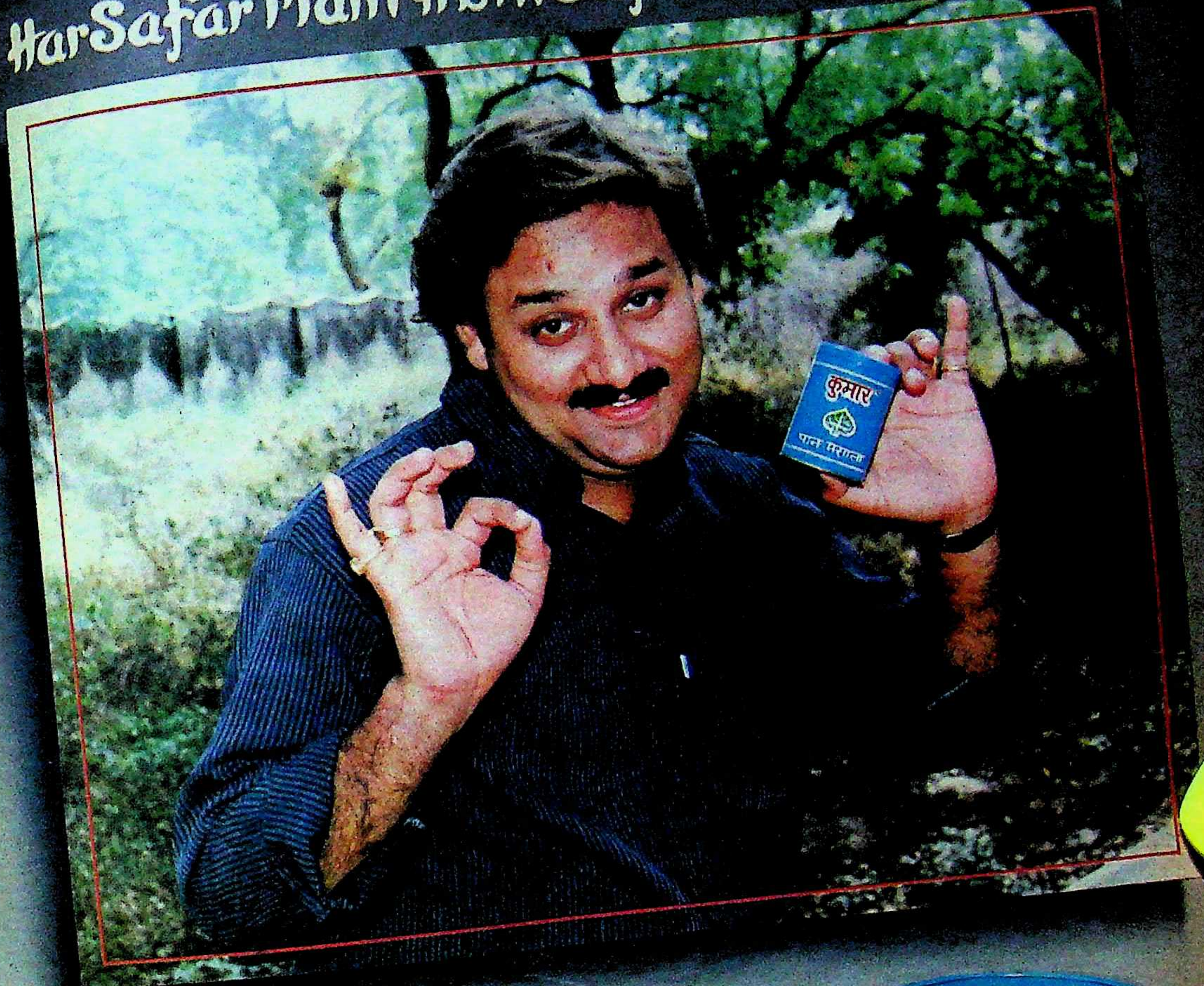

KUMAR®
PAN MASALA
कुमार
पान मसाला
कुमार
पान मसाला
जर्दा मिक्स

KUMAR®

PAN MASALA

Mfd. by— **Kumar Chemicals, Kanpur-208 001**

PHONE No. : 52303, 52305

Statutory Warning : Chewing tobacco is injurious to health

NOTE : DEALERSHIP ENQUIRIES SOLICITED FOR UNREPRESENTED AREAS

साड़ियों के नये-नये रंग
यू.पी. हैण्डलूम के संग

- बनारसी रेशमी साड़ियां (ब्रोकेड एवं तनछुई)
- चन्देरी, सिल्क शिफान, क्रेप डिसीन, इम्बास
- हाथ की बनी हुयी पालिएस्टर ब्लेण्डेड साड़ियां
- सूती, चिकन एवं कटवर्क साड़ियां

हमारे निम्न शो रूम में पधारकर अपना संरक्षण प्रदान करें

● नई दिल्ली 'अरबिन्दो प्लेस, हौजखास, खान मार्केट
● आगरा-संजय प्लेस ● लखनऊ-मेफेयर बिल्डिंग
● कानपुर-पी.पी.एन. मार्केट ● इलाहाबाद-सिविल लाइंस
● वाराणसी-नीचीबाग ● जयपुर- एम.आई.रोड
● चण्डीगढ़-सेक्टर १७ सी. ● भोपाल-टी.टी. नगर,
● बम्बई-कोलाबा ● कलकत्ता-लिन्डसे स्ट्रीट
● मद्रास-माउन्ट रोड ● बिहार-पटना, रांची, जमशेदपुर
● म.प्र. जबलपुर
तथा सारे देश में फैले हुए १५० अन्य शो रूम

HANDLOOMS
यू.पी. हैण्डलूम्स
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
हथकरघा भवन जी.टी.रोड, कानपुर, उ.प्र.

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६; ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५, लखनऊ कार्यालय: बी-१०१, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: २४८८७८, पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५२ (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९१०३५, जयपुर कार्यालय: ए-२०, शांति पथ, तिलकनगर, जयपुर-४, फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

श्री वीरेंद्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक २२
३० नवंबर, १९८९

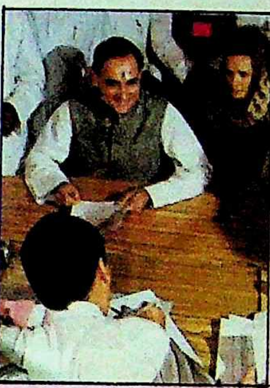

३०

आवरण कथा

बोफोर्स के विस्फोटक दस्तावेजों, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के गहराते मसले और पंत की बगावत के साथ परचे दाखिल करने और नाम वापस लेने का काम समाप्त हो गया। सिर्फ पचासेक को छोड़कर बाकी सभी पुरानों को ही टिकट देने के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ा है। राष्ट्रीय मोर्चा-भाजपा की संयुक्त उम्मीदवार खड़े करने की सहमति ने विपक्षी मतों के विभाजन की संभावना को समाप्त करके कांग्रेस के मार्ग को और दुर्गम बना दिया है। इस निराले आम चुनाव को जीतने के लिए पक्ष-विपक्ष की परस्पर विरोधी व्यूह-रचना का भीतरी हाल:

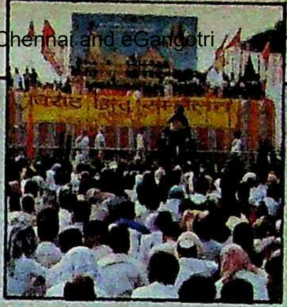

विशेष रिपोर्ट

चुनाव पर सांप्रदायिकता की काली छाया मंडरवाने के लिए क्या विश्व हिंदू परिषद को कांग्रेस ने शह दी है? १७

उत्तर प्रदेश

अमेठी और फतेहपुर की सीटों को समेटे देश की राजनीति के नियंत्रक प्रांत में चुनाव चौसर कैसे बिछी है? ७१

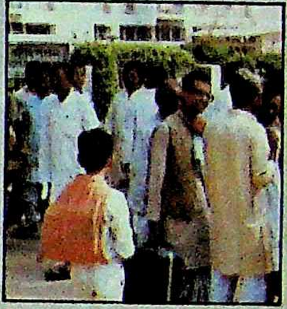

बिहार

भागलपुर में रोजाना मासूम लोगों की निकलती लाशों का शाप चुनाव में किस दल को ग्रसेगा? ६५

राजस्थान

क्या विपक्ष की मोर्चेबंदी आमचुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त करने में कामयाब हो पायेगी? ७७

मध्य प्रदेश

१९८४ में सभी चालीसों सीटें जीतनेवाली कांग्रेस से भाजपा इस बार कितनी सीटें छीनेगी? ८०

सुनिये राजीव गाँधी को चुनिये - N.S.

चुनाव-प्रचार

टीवी-फिल्म के अलावा कांग्रेस द्वारा चुनाव-प्रचार पर किया जा रहा ३०० करोड़ रुपए का खर्च क्या फलदायी हो पायेगा? ९६

दिल्ली दरबार: १०
विशेष रिपोर्ट: ईंट से ईंट बजाने की शह २१
घटनाक्रम: तूफान एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ? २६
चुनाव २७
ज्योतिष गणना: ज्योतिष की निगाह में आम चुनाव ४२
अर्थतंत्र: महंगाई कांग्रेस को मारेगी? ४५
उत्तर प्रदेश: आम चुनाव: माहौल १९६७ जैसा ५७
बिहार: वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र: गढ़ टूटने के आसार ६०
आंध्र प्रदेश: क्या चुनाव इतिहास को दोहरायेगा? ६९
दूरदर्शन: विश्वामित्र: एनटीआर का दूरदर्शनी जवाब ७४
दिल्ली: चुनाव में सीधी मुठभेड़ की संभावना ८३
पश्चिम बंगाल: निर्णय नये मतदाताओं के हाथ में ८७
देश: बोफोर्स की नयी गूंज ९३
प्रसंगवश: चुनावी युद्ध के लिए फिल्मी हथियार ९४

आवरण पारदर्शी
मनमोहन शर्मा

उचित गर्भनिरोधक के बिना विवाहित जीवन आखिर कब तक सुखी रह सकता है ?

कोहिनूर

बेहतरीन गुलाबी कॉन्डोम

आप दोनों का प्यार ही आपको एक-दूसरे के इतने निकट ले आया है। ऐसा प्यार जो विवाह के बन्धन में बन्धने व मिलकर ज़िम्मेदारियाँ निभाने से बढ़ता और सुदृढ़ होता है। किसी भी विवाहित जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है ऐसे दो व्यक्तियों की जो उसे आपस के विश्वास, भरोसे व घनिष्टता से भर दें। साथ ही एक दूसरे को सुखी रखने के लिए इतने समर्पित हों कि एक ऐसे गर्भनिरोधक का चुनाव करें जो दोनों के अनुकूल हो।

ऐसा गर्भनिरोधक जो सम्पूर्ण सुख व सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर पर अनुचित प्रभाव नहीं डालता, कष्टकर डाक्टरी जाँच को आवश्यक नहीं बनाता व दिन गिनने और तापमान मापने की चित्ता व तनाव को दूर रखता है। ऐसा सुरक्षित, आसान व विश्वसनीय गर्भनिरोधक है कॉन्डोम।

KOHINOOR
PINK LUXURY CONDOMS

विश्वसनीय कोहिनूर

हज़ारों युवा दम्पत्ति अपने बच्चों के जन्म में उचित अन्तर रख अपने परिवार का नियोजन विश्वसनीय कोहिनूर के सहारे करते हैं। कोहिनूर आपके मिलन के सुख में बाधा डाले बिना बहुत सहज ढंग से आपको सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करता है। यह उच्च कोटि के लेटेक्स रबड़ से बनाया जाता है। सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक जाँच की जाती है। कोहिनूर के निर्माता आपकी एकांतता व सुरक्षा की आवश्यकता को भलिभाँति समझते हैं। कोहिनूर — इसे नाम लेकर ही खरीदिए और विश्वसनीय कोहिनूर के सहारे निश्चिन्त हो जाइए।

कोहिनूर तीन कॉन्डोम व दस कॉन्डोम के पैकेटों में उपलब्ध है।

परिवार नियोजन — विश्वसनीय कोहिनूर के संग।

TTK उत्पादन

MAA COMMUNICATIONS 915A HIN

माया
दलाली के नये दस्तावेज
चुनाव घोषणा के लिए मजबूर राजीव
क्या बोफोर्स की मार से बच पायेंगे?

राजीव गांधी : क्या बोफोर्स की मार से बच पायेंगे ?

१५ नवंबर की 'माया' मिली। आवरण कथा 'चुनाव घोषणा के लिए मजबूर राजीव : क्या बोफोर्स की मार से बच पायेंगे ?' पढ़ी। आनंद आ गया। 'माया' ने राजीव गांधी द्वारा जल्दी में चुनाव की घोषणा करने के पीछे जो संभावनाएं व्यक्त की हैं, वे सही लगती हैं। राजीव और उनकी चौकड़ी यह जानती थी कि एन राम के दलाली के दस्तावेज छापने से उनकी छवि कितनी धूमिल हुई है ? उनको यह भी डर हो गया था कि १५ जनवरी, १९९० तक तो एन राम सहित देश के सारे अखबार दलाली के दस्तावेजों की झड़ी लगा देंगे, तब तो जो बची-खुची छवि है, वह भी मटियामेट हो जायेगी। दूसरे सारे देश में दंगे हो ही रहे हैं, ऐसे में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने का मौका भी मिल जायेगा। तीसरे विपक्षी अभी तालमेल के लिए छटपटा ही रहे हैं, इसलिए यही सबसे सटीक मौका है, जब चुनाव की घोषणा कर दी जाये। अब जनता को तय करना है कि भ्रष्टाचारी राजीव को वे पुनः गद्दीनशीं करेंगे या जनता के हमदर्द होने का नारा देनेवाले विपक्ष को? **—कानू सान्याल, २ रवींद्रनाथ मार्ग, उड़ीसा**

राजीव के सिक्के : कितने खरे कितने खोटे ?

३१ अक्तूबर की 'माया' मिली। आवरण कथा 'राजीव के सिक्के : कितने खरे कितने खोटे' ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खोखलेपन को बड़े ही सटीक ढंग से उजागर किया है। जिस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की एकता पर ही संदेह हो, वह पार्टी राष्ट्र की एकता, अखंडता का दावा किस बिना पर कर सकती है ? सच कहा जाये, तो राजीव काल ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा से जुड़े हर व्यक्ति के चरित्रहनन का काल रहा। टीएन चतुर्वेदी से लेकर जनरल सुंदरजी तक, सभी राष्ट्र के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों पर सत्ता के दलालों द्वारा उंगली उठायी गयी। ऐसे माहौल में जब सभी सरकारी नेताओं की योग्यता का प्रमाण-पत्र राजीव के प्रति निष्ठा ही हो, तब राष्ट्र के प्रति निष्ठा की कोई कीमत नहीं हो सकती।

अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आरोप-प्रत्यारोप की आंधी जोर से चलेगी। ऐसे में भारतीय मतदाता अपनी जागरूकता और परिपक्वता का प्रमाण किस रूप में देते हैं, समय बतायेगा। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि 'माया' निष्पक्षता से हम पाठकों को अपनी ही शैली में सच्ची जानकारी देती रहेगी। **—शैलेंद्र कुमार तिवारी, हिंदुस्तान मोटर्स, टुआर, हुगुली, पश्चिम बंगाल**

'राजीव के चुनावी सिक्के : कितने खरे, कितने खोटे ?' के अंतर्गत आपने सातों मुख्यमंत्रियों की स्थिति का बिलकुल सटीक वर्णन किया है। सच तो यह है कि इन सातों मुख्यमंत्रियों में से नारायण दत्त तिवारी व शरद पवार को छोड़कर बाकी सभी खोटे हैं। ये पांचों अपने-अपने राज्य में अपनी पार्टी के आपसी अंतर्कलह में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि ये कतई अपने गृह राज्य में चुनावी नाव को किनारे नहीं लगा पायेंगे। **—शैलेश कुमार चौधरी, सोनडियरा, हजारीबाग, बिहार**

'राजीव के चुनावी सिक्के : कितने खरे कितने खोटे ?' पूरा पढ़ा, काफी पसंद आया। अन्य प्रदेशों की बात तो मैं नहीं कर रहा, पर हमारे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में नारायण दत्त तिवारी ही एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ-ही-साथ राजीव को भी उस पार लगाने में सक्षम हैं। **—रमेश चंद्र पाण्डेय, बेलभरिया रामगुलाम, बस्ती, उप्र**

विपक्षी तालमेल : वाम-भाजपा की जंग

३१ अक्तूबर '८९ की 'माया' में 'विपक्षी तालमेल : वाम-भाजपा की जंग' पढ़कर आश्चर्य होता है कि विपक्ष के शीर्ष नेताओं का महान उद्देश्य राजीव गांधी को हटाना है। वे कभी वाम-दक्षिण का भेद भुलाकर एकजुट होने का प्रदर्शन करते हैं, तो कभी विभिन्न दिशाओं से एक दूसरे की कटु आलोचना करते हुए आक्रामक तेवर अपनाते हैं। कदाचित इससे कांग्रेस को ही लाभ होगा।

यदि ऐन वक्त पर तालमेल न हुआ तथा एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा न किया गया, तो बोफोर्स, ठक्कर आयोग, सीएजी मुद्दा तथा भारतबंद इत्यादि मामले विपक्ष की एकजुटता के खोखले नाटक मात्र सिद्ध होंगे। **—विजय प्रताप सिंह, चिरमिरी, सरगुजा, मप्र**

वर्चस्व का अभूतपूर्व प्रदर्शन

'माया' (३१ अक्तूबर, १९८९) में प्रकाशित 'वर्चस्व का अभूतपूर्व प्रदर्शन' पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि भजनलाल को इस रैली ने बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। भजनलाल इतने परेशान क्यों हैं ? लाखों की रैली को हजारों की रैली बता रहे हैं। भजनलालजी यदि देवीलाल की चिंता छोड़कर कुछ जनकल्याण करें, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जब बोफोर्स दलाल राजीव गांधी का जन्म दिन 'युवा दिवस', सोनिया गांधी (विदेशी रानी) का जन्म दिन 'महिला शक्ति दिवस' के रूप में मनाया जा सकता है, तो देवीलाल का जन्म दिन 'संघर्ष दिवस' के रूप में क्यों नहीं मनाया जा सकता ? सच तो यह है कि विपक्ष की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर भीतर-ही-भीतर सहमे हुए ये कांग्रेसी कुछ भी कह सकते हैं। **—संतोष कुमार सिंह, झरिया, बिहार**

वर्जित क्षेत्र की ओर राजनीति का बढ़ता पांव

३१ अक्तूबर का अंक पढ़ा। 'वर्जित क्षेत्र की ओर राजनीति का बढ़ता पांव' पसंद आया। भारत में आज तक 'केंद्रीय जांच ब्यूरो' जैसे महत्वपूर्ण संस्थान तो संदेह के कठघरे में थे, मगर 'सेना' ही कठघरे से दूर थी। लेकिन अब यह लगने लगा है कि सेना की तरफ तथा उसके उच्च अधिकारियों पर जो उंगली उठ रही है, वह शायद राजनीति के गंदे नाले की तरफ जाने को विवश कर रही है। वह दिन दूर नहीं, जब सेना की पकड़ प्रशासन पर भी होगी और हमें विवश होकर उसका मुंह देखना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। **—जीतेंद्र सी जैन, विट्ठल वाड़ी, बंबई**

ट्रांसफर-पोस्टिंग का फूलता-फलता धंधा

'ट्रांसफर-पोस्टिंग का फूलता-फलता धंधा' (३१ अक्तूबर, १९८९) पढ़ा। आंखें फटी-की-फटी रह गयीं। जिस राज्य के प्रशासन में तथा उसके नुमाइंदों में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ हो, उस राज्य का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। फिर वही उत्तर प्रदेश अपने को २० सूत्री कार्यक्रमों के विकास में अपने को देश का सबसे अग्रणी राज्य कैसे घोषित करता है ? क्या ये विकास के आंकड़े भी फर्जी हैं ? इस लेख में आये कथित निलंबित अधिकारी का फिर उसी जगह पर पदस्थापन तथा निलंबन अवधि को छुट्टी तथा कार्य के रूप में प्रदर्शित करना, पूरे भ्रष्ट प्रशासन की कलई खोलता है। **—आफताब आलम खां, फरदहियां, छपरा, बिहार**

चौकीदार से विश्वविख्यात कलाकार

'माया' ३१ अक्तूबर, १९८९ का अंक पढ़ा। इसमें 'गुदड़ी में लाल' उक्ति सार्थक करने वाले उस महान कलाकार के बारे में पढ़कर काफी खुशी हुई। घड़वा कला के माध्यम से जयदेव बघेल ने जो विश्व ख्याति प्राप्ति की, वह वास्तव में काबिलेतारीफ है। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गरीबी, भूख और प्यास के बावजूद साधना में तल्लीन जयदेव बघेल हमारे लिए अनुकरणीय हैं। **—अंजनी कुमार शाम्हो, बेगूसराय, बिहार**

शत्रु बिहार के लिए फरिश्ता साबित होंगे

मैंने ३१ अक्तूबर का अंक पढ़ा। 'माया' ने जो अमिताभ का उदाहरण दिया, वह गलत है। अमिताभ ने स्वयं अपनी छवि खराब की है। यदि शत्रु के इरादे नेक हैं, तो शक नहीं कि आंध्र के रामाराव की तरह बिहार के शत्रु बिहार की जनता के लिए फरिश्ता साबित होंगे। शत्रु ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे जाहिर है कि शत्रु बिहारवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो जनता शत्रु जैसे अभिनेताओं का स्वागत करेगी।

—राजीव वर्मा, इटावा

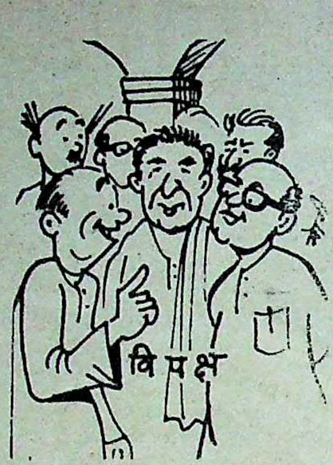

अगर सरकार बोफोर्स तोप नहीं खरीदती तो आज हम हारी हुई जंग जीतने की स्थिति में कैसे आते?

कार्टून: मोनी
साभार: रांची एक्सप्रेस

मुझे विश्वास है कि विवेक-शक्ति धन-शक्ति को परास्त करेगी और जनता की ताकत सत्ता की ताकत का जवाब देगी।—**राजमोहन गांधी, यूएनआई**

राजीव गांधी कल्पनाथ (राय) के लिए कुरसी खाली क्यों नहीं कर देते, ताकि वे वीपी सिंह का सफाया कर दें?—**जनेश्वर मिश्र**

ठेके पर (इंकाके) चुनाव-प्रचार का हश्र वही होगा जो ठेके पर होनेवाले दूसरे कामों का होता है।—**शरद पवार**

व्यक्ति (राजीव) के प्रति वफादार होने का मतलब है देश के प्रति गद्दार होना। दुर्भाग्य से कांग्रेस इसी मर्ज की शिकार बन गयी है।—**कमलापति त्रिपाठी**

नाजायज आदमी काम भी नाजायज ही करता है, इसीलिए राजीव को असंवैधानिक कदम उठाने की आदत पड़ गयी है, जिसकी ताजी मिसाल है लोकसभा भंग किये बिना ही आम चुनाव कराया जाना।—**जार्ज फर्नांडीस**

लोकसभा भंग करने की बात तो कभी मेरे दिमाग में आयी ही नहीं।
—**राजीव गांधी**

यह विपक्ष की पहली जीत है, क्योंकि हमने राजीव सरकार को जनादेश प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया।—**केपी उन्नीकृष्णन**

प्रधानमंत्री चाहते थे कि विपक्ष सकते में आ जाये, पर सफल नहीं हुए, क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे।
—**रामकृष्ण हेगड़े**

अमेठी की जनता को इस बार यह फैसला करना है कि वह महात्मा गांधी की नीतियों के प्रति आस्थावान है या उन लोगों के प्रति, जिन्होंने देश को कत्लगाह बना रखा है।—**राजमोहन गांधी**

राजीव गांधी को तो जाना ही है, हां अब वे दो महीने पहले चले जायेंगे।
—**पी उपेंद्र**

जो भी हो, जो काम हम आठ हफ्तों में करने की योजना बना रहे थे, वह अब हमें चार हफ्तों में ही कर लेना है।
—**यशवंत सिन्हा, जद महासचिव**

लोकशक्ति (जनता) ने इस भ्रष्ट और अक्षम सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा पहले से बना रखा है।—**वीपी सिंह**

मैं मानता हूं कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ाने में लाभ है, लेकिन यह लाभ हमेशा एक ही तरह का नहीं होता।—**लालकृष्ण आडवाणी**

जब व्यापारी नेता बन जाये, तो उन्हें अनिवार्यतः हटा दिया जाना चाहिए।—**सी लक्ष्मन्ना, तेलुगूदेशम सांसद**

आप सबके-सब (विपक्ष) कांच के घर में बैठे हैं।—**केसी पंत**

कभी-कभी उनके (राजीव गांधी के) विचारों को मैं ही भाषा देता हूं।
—**मणिशंकर अय्यर**

हमने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पाये हैं, हम इन्हें धुआं उगलती तोप और दिलचस्प निशान (सुराग) कह सकते हैं।...हम अब शीघ्र ही जाननेवाले हैं कि वह (दलाली की) रकम किसे मिली है।—**एन राम, 'हिंदू' के सह-संपादक**

हे राम! भारत में पत्रकारिता कहां पहुंच गयी है? अब पत्रकार भी प्रेस कांफ्रेंस बुलाने लगे हैं।—**आरजीके, स्तंभ लेखक**

जो बात सामने आयी है, वह यह है कि जो लोग अपना दामन पाक-साफ दिखाते और बड़े-बड़े दावे करते हैं, वे वास्तव में रंगे हुए लोग हैं।—**राजीव गांधी**

निश्चय ही, जैसा कि सब जानते हैं, भारत और विदेशों के सभी प्रधानमंत्री तथा राजनीतिक दल दलाली के तौर पर या दूसरी तरह से धन लेते हैं।—**आरके करंजिया, इंडिपेंडेंट**

इस चुनाव में अन्याय पर न्याय की विजय होगी।—**बालासाहब देवरस**

अगर मैं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ता हूं, पार्टी के अंदर नहीं लड़ता हूं, या कांग्रेस नहीं छोड़ता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझमें माद्दा नहीं है।—**नारायणदत्त तिवारी**

यह भेदभाव का सलूक क्यों? इसलिए कि मैं बोफोर्स सौदे का दलाल नहीं हूं? या इसलिए कि मैं उस वीपी सिंह का बेटा हूं, जिन्हें सत्तारूढ़ दल ने अपना असली निशाना बना रखा है?—**अजेय सिंह**

प्रधानमंत्री तक पहुच पाना बहुत मुश्किल हो गया है।—आगे से बटालियन घेरे हुई है, तो पीछे से इटेलियन (लोग)।—**चतुरानन मिश्र**

प्रधानमंत्री कौन होता है जनता को अधिकार देनेवाला? वह (जनता) तो खुद प्रधानमंत्री को अधिकार देती है।—**राम जेंठमलानी**

दूरदर्शन राजीव दर्शन नहीं है—वह भारत दर्शन है, विश्व दर्शन है।
—**एचकेएल भगत, इंडिया टुडे**

मैं मुस्लिम नेतृत्व की धारणा को खारिज करता हूं। शहाबुद्दीन एक राष्ट्रीय नेता बनने का हौसला क्यों नहीं रख सकता? —**सैयद शहाबुद्दीन, जेंटलमैन**

उर्दू का भविष्य भारत में ही है, न कि पाकिस्तान में जहां वह पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं की भीड़ में खो गयी है।—**अटल बिहारी वाजपेयी, टाइम्स आफ इंडिया**

रिलायंस अब एक अवधारणा बन गया है, जिसमें अंबानी घराना अप्रासंगिक हो गया है।—**धीरूभाई अंबानी, इंडिया टुडे**

यह कहना कि पाकिस्तान के पास बम नहीं है, वैसा ही है जैसे यह कहना कि जिस व्यक्ति ने अपनी बंदूक में गोली नहीं भरी है, वह निहत्था है।—**अमरीकी विशेषज्ञ गेरी मिहालिन**

जब मेरी फिल्में फ्लाप होती हैं, तब मैं बोतल नहीं पटकता, न ही उनके चल निकलने पर मैं खुशी से उछल पड़ता हूं।—**देव आनंद, शो टाइम्स**

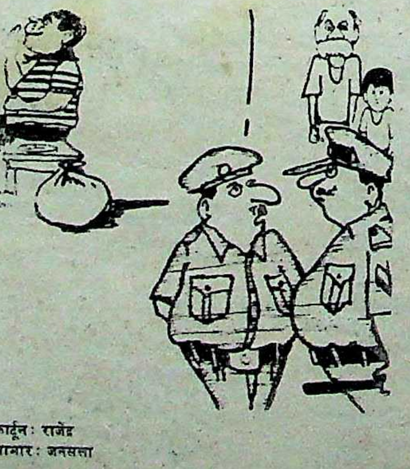

हम क्या कर सकते हैं सर? वह कह रहा है कि उसने चोरी की या नहीं, इसकी वह खुद जांच कर रहा है।

कार्टून: राजेंद्र
साभार: जनसत्ता

डायमंड पाकेट बुक्स में

प्रतिभाशाली उपन्यासकार

राजहंस

का नया उपन्यास

सैलाब

राजहंस
सैलाब
राजहंस

विक्की आनन्द
ग़र्म राख

विक्की आनन्द

का नया उपन्यास

ग़र्म राख

इंसाफ का मंदिर
समीर

समीर

का नया उपन्यास

इंसाफ का मंदिर

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि.
2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

पंडितजी का कोप

पं० कमलापति त्रिपाठी को आयु के बढ़ने से चलने-फिरने या फिर सुनने-बोलने में कितनी भी कठिनाई होती हो, लेकिन अपने राजनीतिक दांवपेंच फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इंका के अंदर, 'खासकर प्रधानमत्री के निकट के लोगों का एक गुट पं० कमलापति को कतई पसंद नहीं करता है। वह बार-बार ऐसी हरकतें करता है, जिससे पंडितजी को मानसिक क्लेश होता है और वे तुरंत उसका बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं।

पिछले दिनों जब उनकी सांसद पुत्रवधू श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी की मृत्यु हो गयी, तो उनके परिवार के लोगों ने चाहा कि कमलापतिजी किसी तरह राज्यसभा के सदस्य हो जायें। लोकपति त्रिपाठी ने अपने पिता की इस इच्छा को मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के जरिये प्रधानमंत्री निवास पहुंचवा दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इसमें कोई खास आपत्ति नहीं थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद, उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव आदि यह नहीं चाहते थे कि पंडितजी को राज्यसभा में लाया जाये। इन लोगों ने पंडितजी के प्रतिद्वंद्वी सांसद रत्नाकर पांडेय को यह जानकारी दी। रत्नाकर पांडेय चूंकि प्रधानमंत्री के बच्चों को हिन्दी पढ़ाने के लिए जाते रहते थे, इसलिए वे सोनिया गांधी के काफी करीब माने जाते हैं। कहा जाता है कि पांडेयजी ने चक्कर चलाकर सोनिया को भड़का दिया।

इधर श्रीमती शीला दीक्षित पंडितजी के पक्ष में हो गयी थीं। उन्होंने प्रेस को भी बता दिया कि पं० कमलापतिजी को राज्यसभा में उप्र से लाया जा रहा है। लेकिन अंत में उनका टिकट कट गया। पंडितजी इससे नाराज हो गये और उन्होंने तुरंत सारनाथ में चंद्रशेखरजी द्वारा आयोजित आचार्य नरेंद्र देव शताब्दी समारोह में भाग लेकर इंकाइयों को जमकर फटकार लगा दी। इसके पूर्व बलराम सिंह को परेशान करने के लिए वे बयान जारी कर चुके थे कि वे पैसे लेकर लोगों को पद दे रहे हैं। वे श्यामलाल यादव से भी बनारस की राजनीति के कारण नाराज थे। उन्होंने कृष्णकांत तथा रामधन के साथ मिलकर यह बयान दे मारा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को कई पत्र लिखकर यह कहना शुरू कर दिया कि किन लोगों को टिकट दिया जाये और किन लोगों को नहीं दिया जाये। इस पर भी जब कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी, "मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने जा रहे विश्व हिंदू परिषद का वहां ९ नवम्बर को जाकर विरोध करूंगा। मेरी लाश से गुजर कर ही वे लोग मस्जिद तोड़ पायेंगे।" विश्व हिंदू परिषद ने पंडितजी को जानकारी भी दी कि उनका मस्जिद तोड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं है। वहां वे केवल मंदिर का शिलान्यास करेंगे। चूंकि यह पंडितजी को भा नहीं रहा था, इसलिए उसे प्रकाश में नहीं लाये। इसी तरह की सूचना उनको आरएसएस के प्रमुख देवरस की तरफ से दी गयी। उसे भी पंडितजी ने दबा लिया। इधर वे जनता दल के अध्यक्ष वीपी सिंह से भी मिले। वीपी सिंह श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त करने तथा बाबरी मस्जिद पर जो उन्होंने 'स्टैंड' लिया था उसके लिए बधाई देने के लिए गये थे। लेकिन उसको उन्होंने छुपाकर इंका को परेशान कर दिया कि पता नहीं वे क्या खिचड़ी पका रहे हैं? इसके बाद वे इंका संसदीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने नहीं गये, जबकि उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि वे बैठक में भाग लेंगे। माखनलाल फोतेदार उनको मनाने गये, लेकिन वे माने नहीं। इसके बाद संसदीय बोर्ड ने उनसे चंदौली (वाराणसी) से चंद्रा त्रिपाठी की सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव को लेकर स्वयं राजीव गांधी उनके घर गये। पंडितजी ने दो दिनों के बाद उस पत्र को भी 'प्रेस' को देकर 'कैश' करा लिया।

पंडितजी के इन सब राजनीतिक दांवपेंचों का पूरा लाभ उनके पुत्र लोकपति त्रिपाठी ने उठा लिया। विधानसभा के इंका प्रत्याशियों की जो सूची बनी, उसमें उंन्होंने अपने आदमियों को घुसवा दिया। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने लोकपति त्रिपाठी से पहले ही अपना समीकरण बिठा लिया है। अब पं० कमलापतिजी की आखिरी इच्छा यही है कि वे किसी तरह लोकपति को उप्र का मुख्यमंत्री बनवा दें। देखना है, पंडितजी अब आगे क्या रंग दिखाते हैं?

बलभूल तिवारी

गुलाम नबी आजाद के यहां भारी भीड़ थी। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ उन लोगों ने भी धरना दे रखा था जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश के नये सपने संजो रखे थे। इस भीड़ को चीरते हुए नारायण दत्त तिवारी आये और आजाद जिस कमरे में थे, उसमें चले गये। आधे घंटे बाद आजाद और बलराम सिंह के साथ तिवारी भी निकले और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। वहां तिवारी द्वारा तैयार की गयी सूची प्रधानमंत्री के सामने रखी गयी, तो प्रधानमंत्री ने बिना हीला-हवाली के उस पर दस्तखत कर दिये। यह सूची विधानसभा के प्रत्याशियों की थी। सूची वीएन गाडगिल को दे दी गयी और गाडगिल ने उसे पार्टी दफ्तर के सूचना पट पर चिपका दिया। सूची में अधिकाश वही नाम थे जो पहले से विधायक थे। सेवादल और युवा कांग्रेस के टिकटार्थियों ने जब सूची को देखा, तो उन्होंने गुस्से में अश्लील नारेबाजी शुरू कर दी। नारों का वार नारायण दत्त तिवारी पर था। इतनी ही देर में कांग्रेस के कुछ पहलवाननुमा लोग आये और सूची को नोच कर तेजी से प्रधानमंत्री आवास की ओर लपके। लेकिन तिवारी ने जो निर्णय ले लिया था, वह अटल था। उन्ही नामों की दूसरी सूची फिर पार्टी कार्यालय में टंग गयी और युवा प्रत्याशी और ३० प्रतिशत के आरक्षण का लाभ उठाने की कामना रखने वाली महिलाएं मुंह ताकती रह गयीं।

दरअसल, कृष्ण चंद्र पंत ने राजीव गांधी के आसपास 'कार्यरत चौकड़ी' के साथ 'राजनीतिक जमींदारी' का जो शब्द बाण छोड़ा है, उसका लक्ष्य नारायण दत्त तिवारी ही बताये जाते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि अब तक अहस्तक्षेप की राजनीति करने वाले नारायण दत्त तिवारी ने इस बार अंगद के पांव की तरह अपनी इच्छा को दिल्ली दरबार में रखा था और उनकी इच्छा को उखाड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। इस एक कदम से तिवारी ने यह दिखा दिया कि वे अब दब कर रहने वाले नहीं, दूसरे अधिकांश वर्तमान विधायकों को उपकृत कर दिया कि उन्हीं की बदौलत उनके टिकट नहीं कटे। यदि कांग्रेस को विधानसभा में बहुमत मिला, तो ये उपकृत विधायक तिवारी के अहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं! चुनाव में क्या होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि कांग्रेस के दिन बहुरे, तो तिवारी लखनऊ रहेंगे या दिल्ली—यह और कोई नहीं, स्वयं तिवारी तय करेंगे। लगता है काफी समय बाद उन्हें याद आया कि उनमें कितना बल है। ◆

एच डी एफ़ सी
वैयक्तिक गृह ऋण

अपना घर पाने का सब से जल्द और आसान उपाय

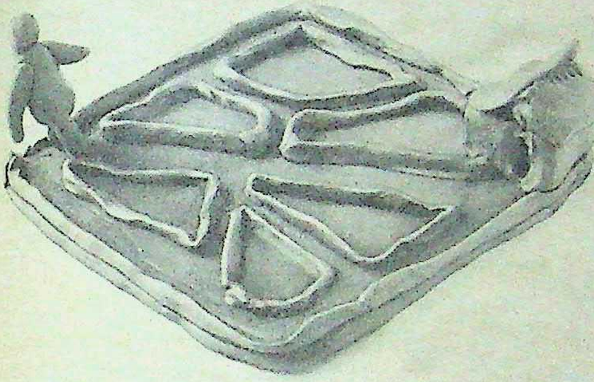

एच डी एफ़ सी समझते हैं कि आप अपने नए घर में जल्दी-से-जल्दी पहुंचना चाहते हैं. हमारी आसान ऋण प्रक्रियाएं इस बात का भरोसा हैं, कि आप को ऋण जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो.

हमारी सुविधाएं आपकी विशेष जरूरतों के अनुसार हैं. अगर आप चाहें तो हमारे कर्मचारी खुशी से आपकी मदद करेंगे. आपकी घर की जरूरतों के लिए हम व्यापक योजना पेश करते हैं. साथ ही देश-भर में फैला सेवा जाल जो यह लाभ आपके दरवाजे तक ले आता है.

● निवास-स्थान के लिए ● ऋण की रकम भुगतान क्षमता के अनुसार ● अधिकतम ऋण 2.5 लाख रु. तक ● भुगतान मासिक किस्तों में 20 वर्ष तक ● ब्याज दर प्रतिवर्ष 12.5% से 14.5% के बीच ● विशेष विकल्प जैसे शॉर्ट-टर्म ब्रिजिंग ऋण सुविधा, टेलिस्कोपिक ऋण योजना और स्टेप-अप भुगतान सुविधा.

हमारी किसी भी शाखा में चले आएं या यह कूपन आज ही डाक से भेज दें.

कृपया मुझे **'एच डी एफ़ सी वैयक्तिक गृह ऋण'** पुस्तिका की एक **मुफ्त** प्रति भेजें.

नाम : ____________________

पता : ____________________

____

____

Code:L MY

एच·डी·एफ़·सी
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

• रजिस्टर्ड ऑफ़िस : बम्बई • शाखाएं : • अहमदाबाद • बंगलूर • भुवनेश्वर • बम्बई (परेल) • कलकत्ता • चंडीगढ़ • कोचीन • कोइम्बत्तूर • गुवाहाटी • हैद्राबाद • हुबली • इंदौर • जयपुर • लखनऊ • मद्रास • नई दिल्ली • पुणे • त्रिवेंद्रम • वडोदरा • वाशी (न्यू बाम्बे)

यहां भेजें : हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

• नई दिल्ली : पालिका भवन, पहली मंजिल, सेक्टर 13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110 066. फ़ोन : 603146, 603147 **• जयपुर :** सी-96, जगन पथ, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302 001. फ़ोन : 77557 **• लखनऊ :** कोहली हाउस, 4-ई, रामतीर्थ मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 394, लखनऊ 226 001. फ़ोन : 35055, 47505 **• चंडीगढ़ :** दूसरी मंजिल, एस सी ओ 1110, 1111, सेक्टर 22-बी, चंडीगढ़ 160 022. फ़ोन : 24843 **• इंदौर :** 9/1/1, एम.जी. रोड, फ़िल एँण्ड फ्लाय पेट्रोल पंप के पास, इंदौर 452 001. फ़ोन : 7784, 7376

ULKA-12706 HIN

जहां हो, खड़े हो जाओ !

रेसकोर्स बनाम बोफोर्स रोड पर दिल्ली दरबार का संसदीय बोर्ड औंधे मुंह हो अपने चुनावी पहलवानों की तलाश कर रहा था। लेकिन दिल्ली दरबार की निगाह 'अपोजीशन चैनल' पर लगी हुई थी। अर्जुन सिंह ने टोका था, "सर, दूसरे के घर में ताकझांक करने से अच्छा है, अपने घर को दुरुस्त किया जाये।" दरबार ने 'हां...हां' करके एक क्षण के लिए अपने कंप्यूटर की तरफ देखा, "ठीक है, आप अपने-अपने पहलवानों के नाम इसमें फीड करें...।" लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी निगाह 'अपोजीशन चैनल' पर जा फंसी, "ठीक किया। चंद्रशेखर को राजा मांडा के एक हाथ और जड़ना चाहिए। यह कमबख्त अजीत सिंह क्यों नही चिल्ला रहा है...।" अर्जुन सिंह ने हार कर गहरी सांस ली, तो दरबारा सिंह ने अपनी मुड़िया दरबार के कान में भिड़ा दी, "अपोजीशन चैनल पर यह तमाशा चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। घड़ी बड़ी तेजी से टिक-टिक कर रही है।" दरबार ने एक क्षण के लिए फिर से अपने कंप्यूटर की तरफ देखा, "हमने इसमें अपने सारे पहलवानों के नाम फीड कर रखे हैं। चूंकि दिखाना है कि हम लोगों की लोकतांत्रिक परंपराओं में गहरी आस्था है, इसलिए आप लोग कसरत करते रहें।" दरबार ने फिर निगाह अपोजीशन चैनल पर जमा ली, "यह क्या भाई साहब (अरुण नेहरू) रायबरेली से फूटकर बिल्हौर की तरफ भाग लिये।" दरबार ने उछल कर आवाज लगायी, "सैम...सैम...।" दाढ़ी खुजलाते हुए कमरे के बाहर से सैम पित्रोदा सामने आ खड़े हुए, "यस बास...!" दरबार ने कहा, "यह बिल्हौर से कौन था?" सैम पित्रोदा ने खटाखट कंप्यूटर के कान मरोड़े। स्क्रीन पर नाम आ गया, "जगदीश अवस्थी...जगदीश अवस्थी...।" दरबार चीखे, "रोक लो इसे। भाई साहब से बाद में निपटा जायेगा।" सैम पित्रोदा के बाहर जाते ही दरबार ने फिर से अपोजीशन चैनल पर अपनी निगाह जमा ली। इस बीच गनी खां चौधरी की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने पास बैठे शंकरानंद से पूछा, "क्या दरबार नेहरू विश्व कप क्रिकेट मैच देख रहे हैं?" शंकरानंद कुछ नहीं बोले। लेकिन दूसरी तरफ बैठे पीवी नरसिम्हा राव फुसफुसा दिये, "नेहरू विश्व कप क्रिकेट नहीं, विपक्षी दलों का मल्ल-युद्ध देख रहे हैं। आपको भी देखना हो, तो उधर सामने जाकर बैठ जायें। वहां से स्क्रीन साफ नजर आती है।" गनी खां ने दो-चार बार अपनी गर्दन घुमाकर इधर-उधर देखा। जब कुछ समझ में नहीं आया, तो शंकरानंद के कंधे पर गर्दन रखकर कहा, "दादा, जब बंगाल की लिस्ट आये, तो मुझे जगा देना।" गनी खां ने खर्राटे भरने शुरू किये, तो चर्र... की आवाज से दरवाजा खुला। जार्ज ने अंदर एक बोरा धकेल दिया। उसमें से मोतीलाल वोरा निकले, "मप्र की सूची पर विचार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं अंदर आ सकता हूं!" दरबार ने अपोजीशन चैनल पर निगाह गड़ाये-गड़ाये कहा, "आइए मोतीलालजी, बैठ जाइए। वह आपका सोलंकी कहां है?" पीछे से प्रदेशाध्यक्ष सोलंकी भी आ गये। अर्जुन सिंह को जब वोराजी ने नमस्कार किया, तो उन्होंने अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपनी मुड़िया हिला दी। दरबार ने अपोजीशन चैनल पर से बिना निगाह हटाये कहा, "करें...करें। मप्र की सूची पर विचार करने की औपचारिकता को जल्दी पूरा कर लीजिए।" सैम ने आकर कंप्यूटर के कान मरोड़े, तो उसमें उम्मीदवारों की सूची निकलनी शुरू हो गयी। वोराजी निगाह गड़ाये हुए सूची देख ही रहे थे कि बीच में चीख पड़े, "सर, रायगढ़ से पुष्पा देवी कैसे चुनाव लड़ेगी?" वोराजी की चीख पर दरबार चौंक पड़े, "क्यों क्या वह वीपी सिंह के साथ चली गयी है?" वोरा के पहले ही अर्जुन सिंह बोल पड़े, "नहीं सर, वह पूरी तरह अपने साथ है। वोराजी ने उनकी बहिन कमला देवी को अपनी सरकार से निकाल दिया था। इसलिए

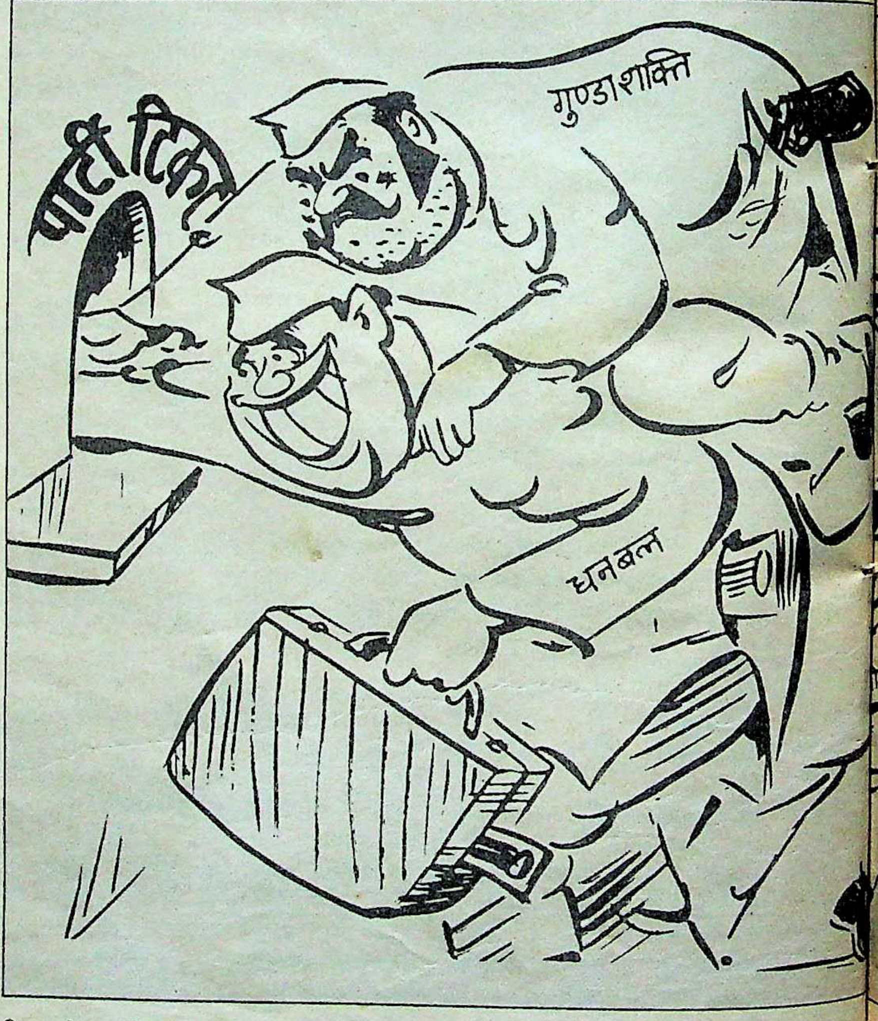

इनकी पुरानी खुंदक है। ठीक है वोराजी, आपकी कमलाजी से खुंदक है। लेकिन पुष्पाजी ने आपका क्या बिगाड़ा है?" दरबार ने फिर से अपनी मुड़िया को अपोजीशन चैनल की तरफ फेर लिया, तो वोरा पंचम में चिल्लाये, "सर, यह बात नहीं है। अरे पुष्पा देवी तो अपने दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ाये आपके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बिस्तर तोड़ रही हैं। वे अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कैसे कर पायेंगी?" दरबार का ध्यान अपोजीशन चैनल पर ही लगा हुआ था। इसलिए उनकी तरफ से कोई 'हां-हूं' नहीं आयी। अर्जुन सिंह ने आहिस्ता से कहा, "पुष्पाजी चारपाई पर लदकर अपने चुनाव क्षेत्र में घूमेंगी। उससे एक सहानुभूति लहर पैदा होगी और वे चुनाव जीत जायेंगी।" वोरा और आगे कुछ कहें कि उनके दायें-बायें मणिशंकर अय्यर और आरके धवन आकर खड़े हो गये। दोनों ही समवेत स्वर में बोले, "आपका समय पूरा हो गया है। आप बाहर जा सकते हैं। वोराजी आपको यहां औपचारिकता निभाने के लिए बुलाया गया था, आप यहां प्रवचन क्यों देने लगे? कृपया उठें और बाहर जायें। आपके पीछे उप्र की सूची पर विचार करने के लिए बलराम सिंह खड़े हुए हैं। अभी-अभी नयी दिल्ली तिवारी पहुंचने वाले हैं।" वोराजी उठे। उनका बोरा सामने किया गया। उसमें वे बैठे और रफूचक्कर हो गये। अपोजीशन चैनल पर निगाह जमाये-जमाये दरबार ने बलराम सिंह का अभिवादन स्वीकार किया। बलराम सिंह जब तक यह बतायें कि नयी दिल्ली तिवारी संतूर होटल में सो रहे हैं, उसके पहले दरबार चीख पड़े, "यह क्या? पं० कमलापति त्रिपाठी से इस वीपी सिंह का क्या लेना-देना!" अर्जुन सिंह ने तुरंत नहले पर दहला मार दिया, "सर, हम लोगों को कमलापतिजी पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको राज्यसभा में ले भी आते, तो भी वे डंक मारते ही रहते।" नरसिम्हा राव का ब्राह्मणत्व जाग उठा, तो वे बोल पड़े, "वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं कुछ निवेदन करूं।" अर्जुन सिंह फिर लपके, "फोतेदारजी को तो उनके पास भेजा गया था। उन्होंने बोर्ड की बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया। अब क्या हम लोग जाकर उनके तलुवे चाटें!" नरसिम्हा राव दृढ़ता से बोले, "जी हां, हम लोग उनके तलुवे ही चाटें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका पूरा लाभ विपक्ष उठा लेगा। इस समय आपके समर्थन में ब्राह्मण समुदाय पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। अगर कमलापतिजी नाराज हो गये, तो फिर काफी मुश्किल हो सकती है!" अर्जुन सिंह ने फिर से बात काटने की कोशिश की, लेकिन दरबार ने उनको रोक दिया, "ठीक है। मैं उनके पास जाऊंगा।" अर्जुन सिंह को पसीना आ गया।

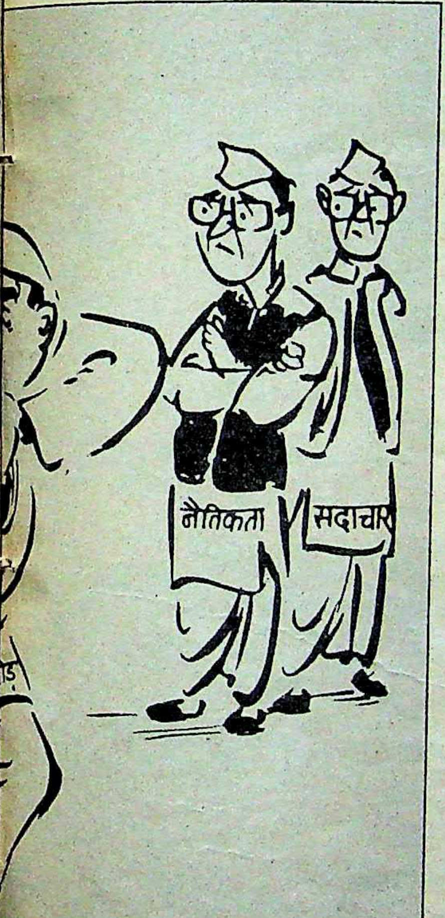

साभार: अमर उजाला

जब दिल्ली दरबार कमलापतिजी से भेंट करने के लिए अपनी विदेशी जीप पर दरबार के बाहर निकले, तो भारी भीड़ इधर-उधर फैली हुई थी। हर लल्लू-जगधर टिकटार्थी बना ईरान-तूरान की उड़ाये हुआ था, "गुरु, ले दे के अपना टिकट ठीक कर लिया है। अगर यहां से नहीं मिला, तो जनता दल से तो टिकट पक्का ही है। राजा मांडा कल रात एक घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा कि भैया तुम लड़ जाओ। वहां से बस तुम्हीं जीत सकते हो। लेकिन उसी समय आरके धवन ने बुलवा लिया। धवन भी पीछे पड़े हैं कि तुम इधर के टिकट पर ही लड़ो। अब चूंकि माल-पानी इधर ज्यादा है, इसलिए मैंने भी इधर का ही मन बना लिया है। अगर इधर से कुछ हीला-हवाली हुई, तो उधर से टिकट लेकर इनके भूसा भर दिया जायेगा।" दिल्ली दरबार की विदेशी जीप जब तेज रफ्तार से निकली, तो सारे टिकटार्थी अधपके चावलों की तरह छिटक गये, "दरबार का तेल चुक गया है, लेकिन धार अभी तक बनी हुई है। अरे, हम लोग इसी के तो कायल हैं। रस्सी जल गयी, लेकिन बल उसी तरह बरकरार है।"...

दरबार में बैठे संसदीय बोर्ड के चेहरे पर संतोष था। अर्जुन सिंह ने प्रस्ताव रखा था कि सैम से कहा जाये कि वे कंप्यूटर से सूची निकालें। दरबार की निगाह अभी भी 'अपोजीशन चैनल' पर लगी हुई थी। उन्होंने गर्दन हिला कर सैम पित्रोदा को इशारा किया कि सूची निकाल दो। सैम ने करीब आकर कंप्यूटर के कान मरोड़े, तो उसने उनको करेंट मार दिया। सैम झटका खाकर दूर जा गिरे। उनकी घिग्घी बंध गयी। बोर्ड में हंगामा मच गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कंप्यूटर के करीब जाये। शंकरानंद की तरफ से सुझाव आया, "हम लोगों से यह कंप्यूटर देवता नाराज लगते हैं। इनकी तुरंत आरती उतारी जाये।" इस प्रस्ताव पर सभी की आम सहमति हो गयी। धवन ने तुरंत आरती लाकर करुणाकरण के हाथ में पकड़ा दी। लेकिन उसे तुरंत श्रीमती चंद्रशेखरन ने छीन लिया, "औरतों को टिकट नहीं दे रहे हो, तो कम-से-कम आरती उतारने का अधिकार तो मत छीनो।" कंप्यूटर देवता की आरती शुरू हो गयी—"ओम जय कंप्यूटर देवा! भक्तजनों के संकट दूर करो। ओम जय कंप्यूटर देवा...।"

कंप्यूटर देवता की आरती को ६२ घंटे हो चुके थे। वह थोड़ा-सा पसीजा, तो उसने कुछ नाम उगले। लेकिन उस समय तक नाम भरने की आखिरी घड़ी टिक-टिक करती हुई सिर पर खड़ी थी। दरबार अभी भी अपोजीशन चैनल पर निगाह गड़ाये बैठे थे। "अच्छा तो अमेठी में गांधी को गांधी से भिड़ा दिया। वीपी सिंह तेरी इस अपील को मैं नहीं चलने दूंगा कि—हे अमेठी वालो, इन दोनों में ढूंढ़ो कि असली गांधी कौन है?" जब संसदीय बोर्ड की कुछ नहीं चली, तो उन्होंने अपोजीशन चैनल के तार काट दिये। अपोजीशन चैनल जब ठप हो गया, तो दरबार बहुत कस कर भड़के, "यह क्या! अपोजीशन चैनल का तार किसने काटा...।" सभी ने समवेत स्वर में कहा, "हे करुणानिधान! आपका कंप्यूटर पूरी तरह फेल हो चुका है। नाम भरने की तारीख सिर पर खड़ी हुई है।" दिल्ली दरबार ने कुछ सोच कर आदेश दिया, "जो जहां है, वहीं से खड़ा हो जाये।" सब लोग खड़े हो गये और कंप्यूटर देवता की आरती फिर से शुरू हो गयी।

—दरबारी लाल

देश

१६ अक्तूबर : निर्वाचन आयोग द्वारा दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों एसएस धनोआ और वीएस सैगल की नियुक्ति। दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की २०० शाखाओं में वेतन संबंधी मामले को लेकर हड़ताल।

१७ अक्तूबर : निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव २२ नवंबर को कराने की घोषणा।

१८ अक्तूबर : उड़ीसा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व मंत्री ६५ वर्षीय दिव्य लोचन शेखर देव का निधन।

१९ अक्तूबर : असम गण परिषद के सांसद सैफुद्दीन अहमद पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित।

२० अक्तूबर : पूर्व विदेशमंत्री श्याम नंदन मिश्र और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री आर गुंडूराव कांग्रेस-इ में शामिल। बोफोर्स संबंधी विवाद को लेकर 'द हिंदू' के निदेशक मंडल द्वारा अखबार के संयुक्त संपादक एन राम मुअत्तल।

२१ अक्तूबर : पुणे की अदालत में न्यायाधीश वीएल रुइकर द्वारा जनरल एएस वैद्य हत्याकांड में हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा को मौत की सजा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री कांग्रेस-इ के नजीर अहमद सिद्दीकी जनता दल में शामिल।

२२ अक्तूबर : डा० एमवी रमन्ना रेड्डी को पुनः तेलुगूदेशम पार्टी में लिये जाने पर विधायक एन वरद राजुलु रेड्डी द्वारा पार्टी से इस्तीफा।

२३ अक्तूबर : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी सुश्री ललिता बोस जनता दल में शामिल। भूतपूर्व कृषि मंत्री राव वीरेंद्र सिंह जनता दल में शामिल।

२४ अक्तूबर : पूर्व सेना प्रमुख ७५ वर्षीय जनरल जीजी बेवूर का निधन।

२५ अक्तूबर : सीपीआई की सुप्रसिद्ध नेता ५७ वर्षीय श्रीमती अंजलि राय का निधन। भारतीय शांति सेना के १००० जवान पूर्वी लंका के ट्रिंकोमाली क्षेत्र से भारत के लिए रवाना।

२६ अक्तूबर : उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष त्रिलोक चंद्र जनता दल छोड़कर कांग्रेस-इ में शामिल।

२७ अक्तूबर : आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी० नारायण राव द्वारा पद तथा तेलुगूदेशम पार्टी से इस्तीफा।

२८ अक्तूबर : विभिन्न महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण एवं वनमंत्री जेडए अंसारी द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ तथा बलात्कार की कोशिश करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। गुजरात में कांग्रेस-इ के वरिष्ठ मंत्री महंत विजय दास द्वारा पार्टी से इस्तीफा।

२९ अक्तूबर : आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी नारायण राव द्वारा कांग्रेस-इ में शामिल होने का निर्णय।

३० अक्तूबर : रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत असंतुष्ट, लोकसभा का चुनाव न लड़ने की घोषणा।

३१ अक्तूबर : डा० अरुण मुखर्जी सीबीआई के नये निदेशक। गोवा के चार प्रमुख कांग्रेस नेताओं फ्रांसिस वेलाडरिस, डा० बब्बन पारुलेकर, डा० कामत चरणकर, विश्वनाथ लवाडे राज्य विधानसभा के लिए पार्टी टिकटों के वितरण पर असंतुष्ट, पार्टी से इस्तीफा।

एन राम

राव वीरेंद्र सिंह

जेआर जयवर्धने

बेनजीर भुट्टो

विदेश

१६ अक्तूबर : जान पी सेसे नार्वे के नये प्रधानमंत्री नियुक्त। पाकिस्तान के बशीर खान बाबर भारत में पाकिस्तान के नये उच्चायुक्त नियुक्त।

१७ अक्तूबर : उत्तरी कैलीफोर्निया (अमरीका) में भयंकर भूकंप, ३०० लोग मरे, ४०० जख्मी।

१८ अक्तूबर : पूर्वी जर्मनी सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव एरिक ओनेकर का इस्तीफा मंजूर, पोलित ब्यूरो के दो सदस्य जोकिम हरमैन और गुंयर मिन्ताग पद से बर्खास्त। राष्ट्रमंडल शिखर देशों की बैठक प्रारंभ, नाइजीरिया के एमेका अन्याओकू राष्ट्रकुल महासचिव निर्वाचित।

१९ अक्तूबर : ७३ वर्षीय स्पेनिश लेखक कामिलो होजे सेला १९८९ के नोबुल (साहित्य) पुरस्कार से सम्मानित। हंगरी की संसद द्वारा साम्यवादी शासन समाप्त, देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू, हंगरी का नया नाम रिपब्लिक आफ हंगरी हुआ।

२० अक्तूबर : श्रीलका संसद ने आपात स्थिति की अवधि एक महीने और बढायी।

२१ अक्तूबर : राष्ट्र मंडलीय देशों के २७वें शिखर सम्मेलन मे राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित 'धरती रक्षा कोष' स्वीकृत।

२२ अक्तूबर : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने का राजनीति से संन्यास तथा यूनाइटेड नेशनल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।

२३ अक्तूबर : अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को और अधिक विस्तृत करने के लिए चीन द्वारा तीन नये उपग्रह प्रक्षेपित करने का निर्णय।

२४ अक्तूबर : जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव एगोन केन्त्स राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित।

२५ अक्तूबर : पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा राज्य श्रममंत्री तारिक मगसी अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर बेनजीर सरकार को ब्लैकमेल करने के आरोप में बर्खास्त।

२६ अक्तूबर : चीनी एयरलाइंस के बोइंग-७३७ विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ५६ व्यक्तियों की मृत्यु। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के ९८ सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रीय असेम्बली में पेश।

२७ अक्तूबर : सोवियत फिल्म 'जोरोग्रैड' शिकागो इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित।

२८ अक्तूबर : 'लिट्टे' द्वारा शांति समिति में भाग लेने से इनकार, श्रीलंका सरकार से उत्तरी-पूर्वी प्रदेशों की प्रांतीय परिषद के लिए पुनः चुनाव कराने की मांग।

२९ अक्तूबर : दक्षिण अफ्रीका में १० हजार व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन।

३० अक्तूबर : उत्तरी अल्जीरिया में भूकंप आने से ३० व्यक्ति मृत, ३०० जख्मी, हजारों बेघर। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टर पंथियों और छात्रों में संघर्ष, ५० जख्मी।

३१ अक्तूबर : पाकिस्तानी सेना द्वारा १ एवं २ नवंबर को इस्लामाबाद अपने नियंत्रण में रखने का फैसला, नेशनल एसेंबली द्वारा बेनजीर सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्तावपर विचारोपरांत परिस्थितियां बदलने की उम्मीद।

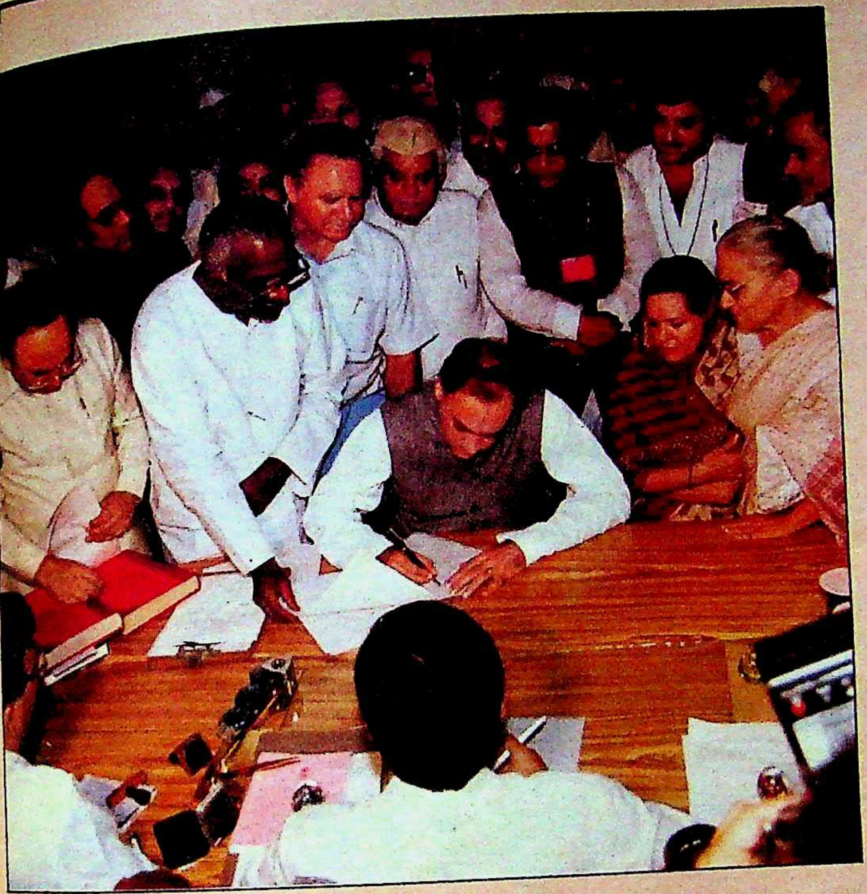

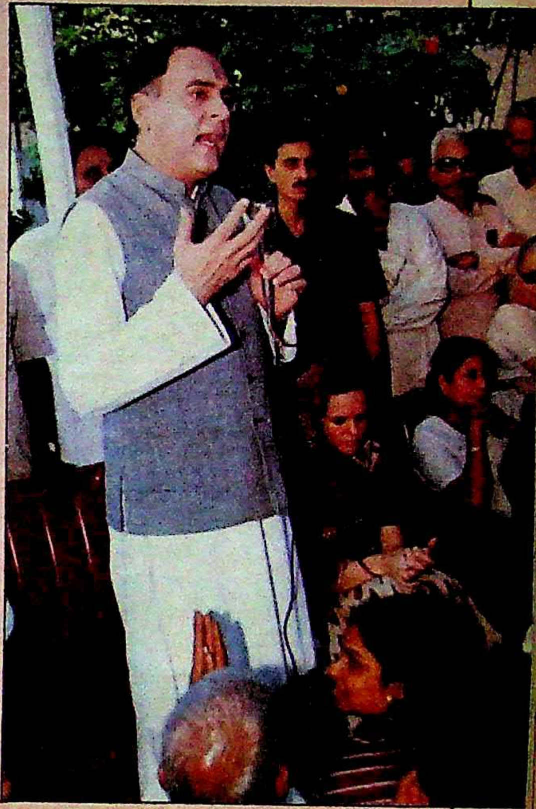

तैयार हो जाओ : नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजीव गांधी।

छाया : राजेंद्र कुमार

मैदान में प्रवेश : २५ अक्तूबर को सुल्तानपुर में अमेठी ससदीय क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करते हुए राजीव गांधी। पीछे खड़े हैं (बायें से एक छोड़कर) पी शिवशंकर, फोतेदार, नारायण दत्त तिवारी, बलराम सिंह और सतीश शर्मा।(ऊपर बायें)

छाया : राजेन्द्र कुमार

शुभकामनाएं : नामांकन के लिए पहुंचे राजीव गांधी का स्वागत।

छाया : मनमोहन शर्मा

चुनाव आयोग द्वारा नौवीं लोकसभा और ५ विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा के बाद वर्तमान सांसदों-विधायकों को अपने टिकट बरकरार रखने की चिंता थी, तो ५ साल से सत्ता में प्रवेश के लिए बाट जोह रहे नये प्रत्याशियों को टिकट पाने की लालसा सता रही थी। क्योंकि टिकटों की हाट राज्यों की राजधानी से हटकर देश की राजधानी में चली गयी थी, इसलिए सभी रास्ते दिल्ली की ओर जाने लगे। कोट, पैंट

और सफारी की जगह खादी के लकदक कपड़ों में सजे और पैरवीकारों से लदे झुंड विमानों-ट्रेनों-बसों से पहुंचने लगे दिल्ली में और शुरू हो गयी जोड़-तोड़, छीना-झपटी और खरीद-फरोख्त। प्रांतों के दिल्ली स्थित 'भवनों' और अन्य विश्राम स्थलों के सामने तो टिकटार्थियों के मेले लगे ही, टिकट दिलाने में सक्षम लोगों के घरों पर भी ठेलमठेल हुई। जब कोई चीज दुर्लभ होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बिचौलियों की तो जरूरत पड़ती ही है, इसलिए दलाली के माहौल में दलाल चांदी काटें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है! भीतरी खबर रखनेवालों का कहना है कि टिकटों की कीमत एक से पांच लाख तक

उत्तर प्रदेश भवन
U.P. BHAWAN

टिकट के लिए भागदौड़ : उत्तर प्रदेश भवन में टिकटार्थी।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

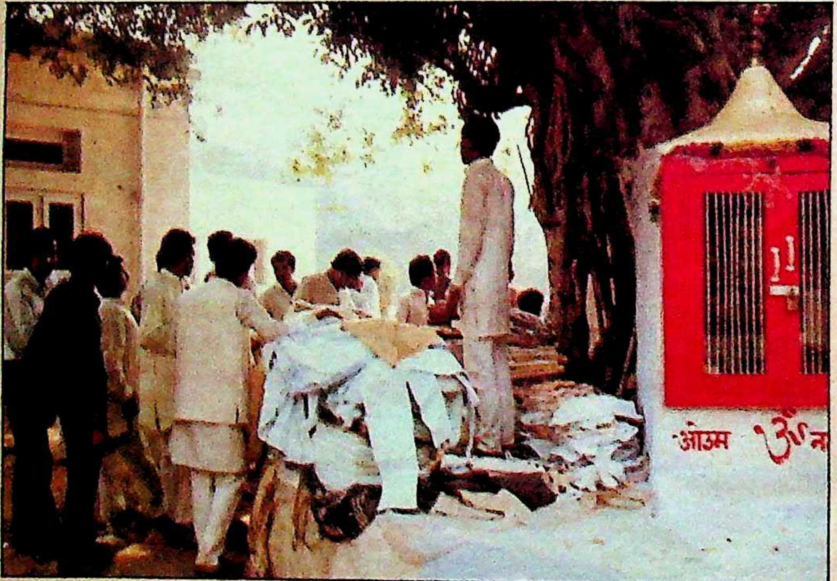

चुनावी भेष : अभाकांक के अहाते में खादी वस्त्रों की बिक्री।

छाया : मुनील सक्सेना

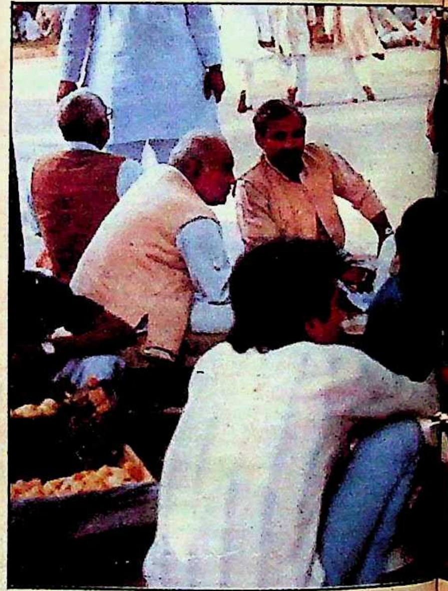

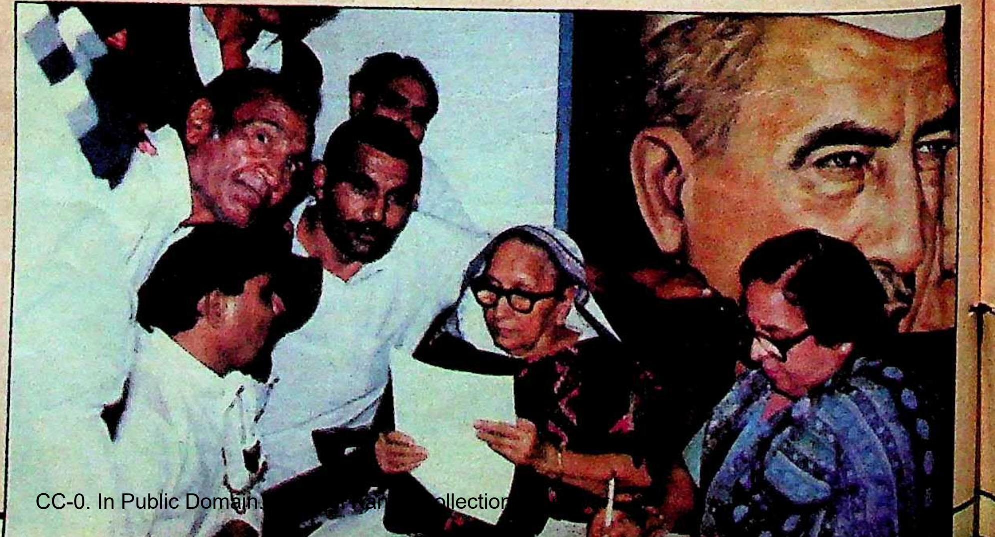

माताजी टिकट दिला दीजिए : स्व० चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी से टिकटार्थियों का अनुरोध।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

Digitized by eGangotri

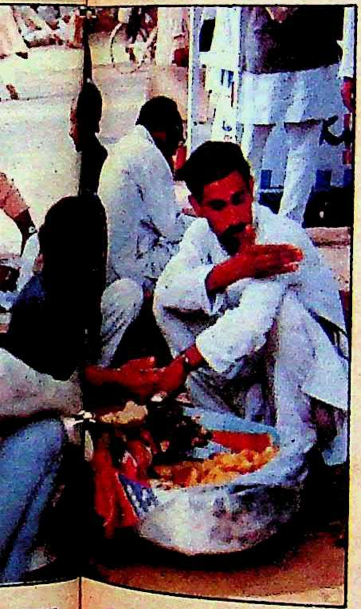

सत्ता की चाट :
उप्र भवन के सामने टिकटाकांक्षी
भूख मिटाते हुए।

छाया: सुनील सक्सेना

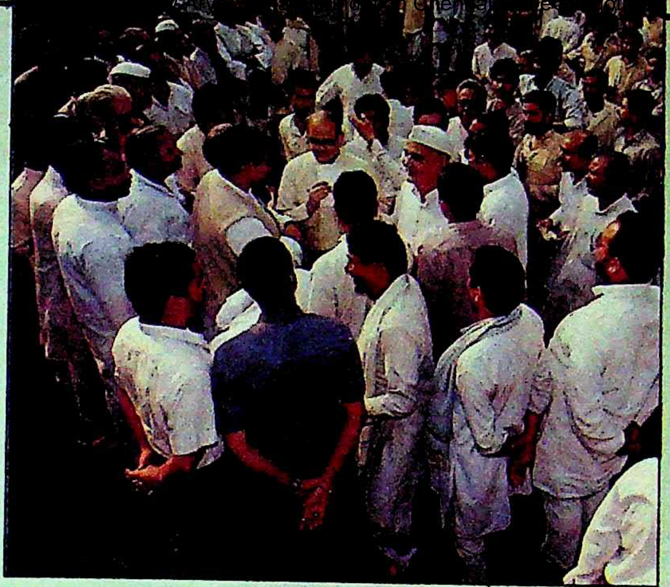

पहुंची। विधानसभा के लिए एक से तीन लाख और लोकसभा के लिए तीन से पांच लाख। यों चुनाव आयोग ने लोकसभा के लिए अधिकतम खर्च डेढ़ लाख और विधानसभा के लिए अधिकतम पचास हजार निर्धारित कर रखा है, लेकिन इस देश में हर काम बाकायदा बेकायदा होता है, इसलिए नियम सब कागज पर धरे रह जाते हैं। सबको मालूम है कि राजनीति अब धंधा है, जिसमें चुनाव के समय एक बार निवेश करा दिया और वह फल गया, तो हजार गुना लाभांश कहीं नहीं गया। इसलिए मन सत्ता में अटकाकर कुछ लोगों ने टिकट पाने के लिए तन-धन जुए में लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

किस-किस को
टिकट दूं? : वीपी सिंह को
घेरे खड़े नेता।

छाया: एस पाल

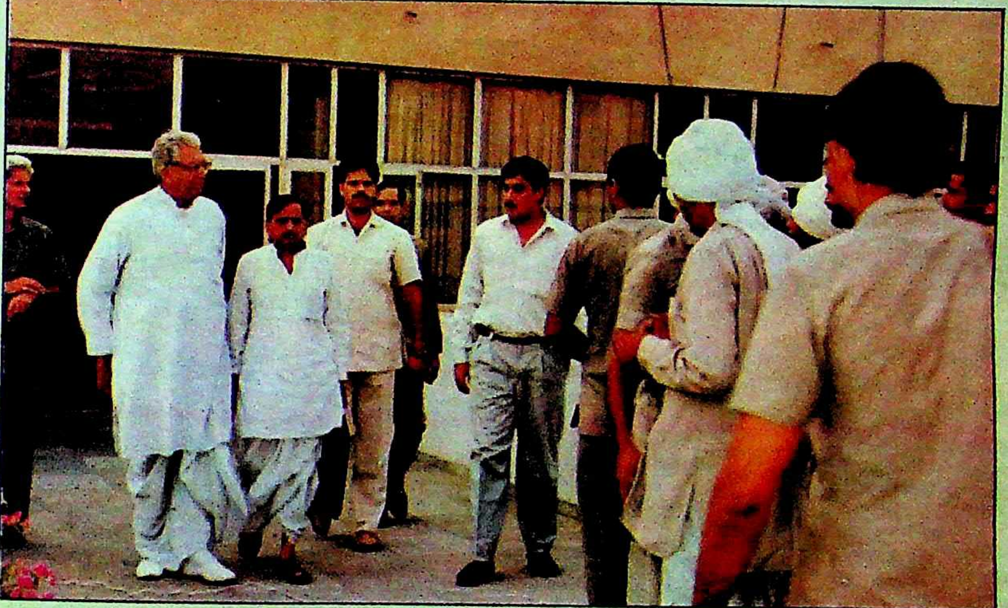

सत्ता का स्रोत :
हरियाणा भवन के सामने
कतारबद्ध टिकटार्थी।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

सबको टिकट चाहिए :
टिकट के लिए
मुलायम सिंह के सामने हाथ
उठाये खड़े टिकटार्थी।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

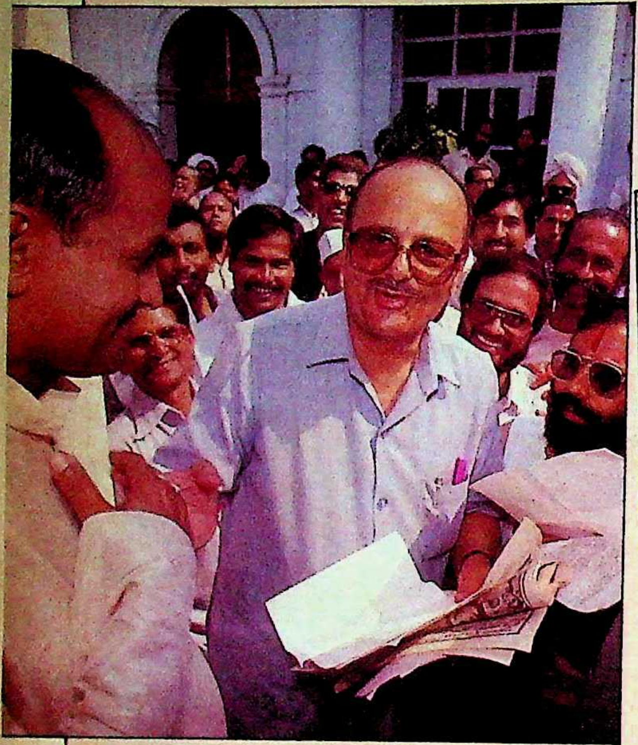

नयों के लिए जगह कहां है ? : कांग्रेसी टिकटार्थी और अर्जुन सिंह।

छाया: एस पाल

साधनों की कमी नहीं : कांग्रेसी अभियान के लिए तैयार खड़ी जीपें।

छाया: सुनील सक्सेना

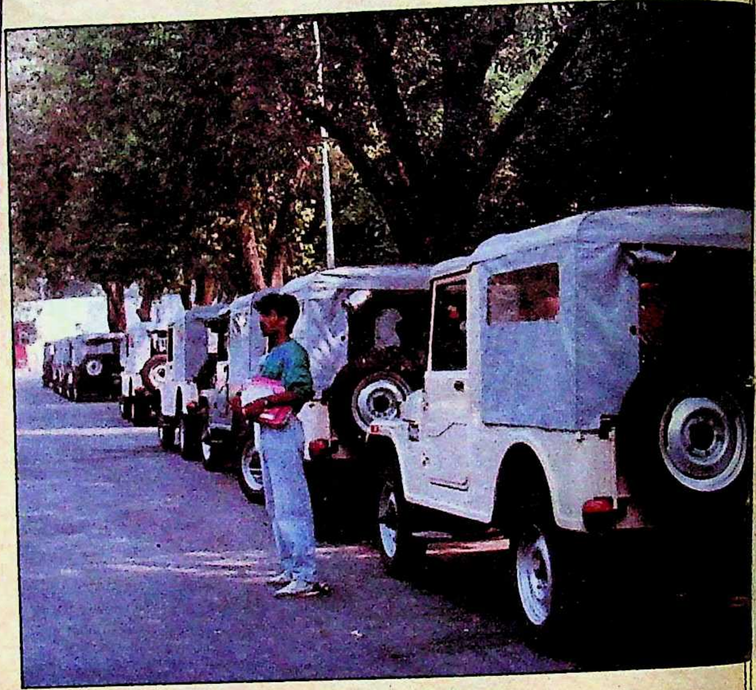

बिहार भवन में खटोले बिछाये बैठे टिकटार्थी।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

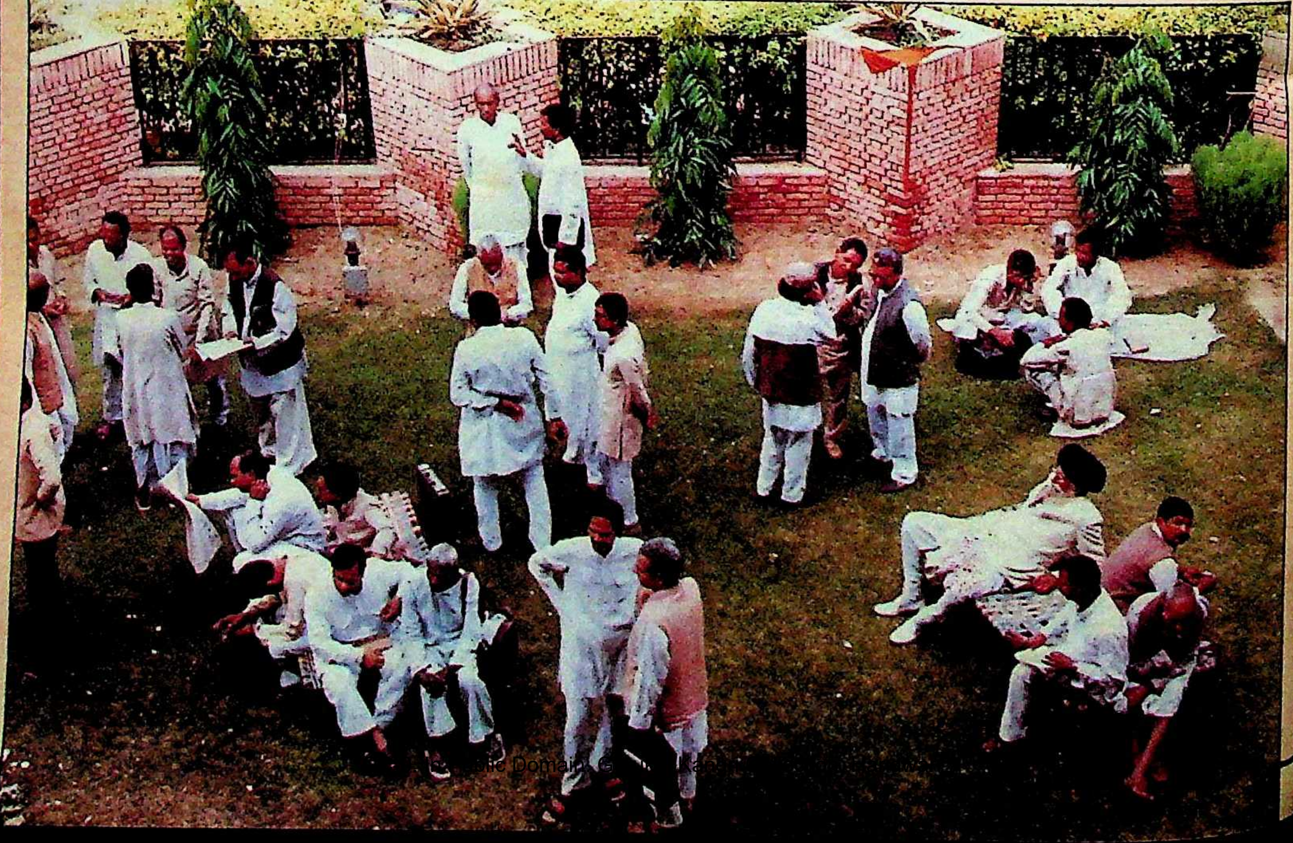

राम जन्मभूमि

वोट का धर्म

देश के विभिन्न भागों में हुए दंगों के कारण रामशिला पूजन और राम-जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की घोषणा चुनाव के समय सर्वाधिक विवाद का विषय बनी है। आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद की इस योजना को कांग्रेस-इ हवा दे रही है। परिषद इस आरोप का खंडन करती है, लेकिन हालात क्या संकेत कर रहे हैं? क्या परिषद के इस अभियान से सर्वाधिक चुनावी लाभ कांग्रेस-इ उठा रही है?

हिंदू वोट बैंक का भरोसा: रामशिला पूजन करते भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी

"सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनायेंगे", एक वक्ता माइक से आह्वान करता है और बजरंग दल की भारी भीड़ हुंकार उठती है, "सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनायेंगे।"

इस एक साधारण से प्रतीत होनेवाले नारे ने भारत की राजनीति को एक विकट मोड़ पर ला खड़ा किया है। राजनीतिज्ञों की नींद हराम है। आम हिंदू उलझा हैं। मुसलमान भयभीत और नाराज है तथा हिंदू कट्टरवाद का तांडव चरमोत्कर्ष पर है। उज्जैन, हल्द्वानी, बदायूं, जयपुर, कोटा, मेहसाना, रतलाम, खरगोन, महू, सीतामढ़ी, भागलपुर आदि जगहों को सांप्रदायिकता ने जा डसा है और यह जहर अभी फैलता ही जा रहा है। आग में घी का कार्य कर रही है विश्व हिंदू परिषद, जिसका वर्तमान मूलमंत्र है—'राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहां विश्राम।"

बूटा सिंह का दबाव: विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का सिर्फ एक लक्ष्य है: पांच सौ साल पुरानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर, वहां पर राम मंदिर बनाया जाये। यदि इस कार्य से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो यह परिषद की जिम्मेदारी नहीं। परिषद का कहना है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर उस स्थान पर बनायी गयी, जहां श्रीराम का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध समाजवादी नेता मधु लिमये कहते हैं, "आज तक यह नहीं मालूम कि जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में किस स्थान विशेष पर पैदा हुए थे। फिर विश्व हिंदू परिषद के नेता किस प्रकार कहते हैं कि राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ, जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है।" यह ठीक है कि धर्म का स्रोत धर्मशास्त्र और आस्था है और इस दृष्टि से अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। धर्मप्राण लोगों का वहां मंदिर बनवाना भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन अदालत ने जहां यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दे रखा है, वहां मंदिर बनवाने की जिद, और वह भी देशभर में शिलापूजन के प्रदर्शनों के साथ, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। गत छह सप्ताहों में अनेक राज्यों में ३०० व्यक्ति मारे जा चुके हैं, पर विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने के अपने कार्यक्रम पर अटल है। आश्चर्यजनक रूप से दंगे सिर्फ कांग्रेस-शासित राज्यों में हो रहे हैं। जनता दल का आरोप है कि कांग्रेस दंगों को जानबूझकर भड़का रही है, ताकि चुनावों में वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बंट जायें और बोफोर्स दलाली, महंगाई और कुप्रशासन के मुद्दे गौण हो जायें। इस आरोप का समर्थन विश्व हिंदू परिषद की समर्थक भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन यह काफी प्रचारित है कि गृहमंत्री बूटा सिंह विश्व हिंदू परिषद पर दबाव डाल रहे हैं कि वह ९ नवंबर को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन करे व अपने शिलान्यास कार्यक्रम पर अटल रहे। अशोक सिंघल की परेशानी यह बतायी जाती है कि वे बूटा सिंह के दबाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके भाई बीपी सिंघल का पूरा कैरियर इस समय बूटा सिंह के हाथ में है। गृह मंत्रालय ने बीपी सिंघल को अरुण नेहरू के साथ चैकोस्लोवाक पिस्तौल घोटाले में फंसा रखा है। मामले की जांच इस समय केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है, जोकि बूटा सिंह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूत्रों के अनुसार धमकी सीधी है कि यदि अशोक सिंघल बूटा सिंह के इशारे पर नहीं चले, तो उनके भाई को जेल की हवा भी खिलायी जा सकती है।

अशोक सिंघल की दूसरी बड़ी परेशानी यह मानी जाती है कि वे शिलान्यास के समय सुरक्षा के लिए बूटा सिंह पर बुरी तरह आश्रित हैं। यदि गृहमंत्री चाहें, तो शिलान्यास पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और तदुपरांत हिंसा पर पुलिस द्वारा। अशोक सिंघल सहित विश्व हिंदू परिषद के अन्य नेताओं को जेल में डाल सकते हैं और यदि अशोक सिंघल मान जायें, तो बूटा सिंह शिलान्यास को पूरी सुरक्षा प्रदान कर कार्यक्रम सफल बना सकते हैं। पर इसका एक अर्थ यह भी होगा कि कांग्रेस शिलान्यास की सफलता की वाहवाही खुद लूटेगी तथा विश्व हिंदू परिषद की पारंपरिक हितैषी भाजपा की वोट की राजनीति खटाई में पड़ जायेगी। पर इसके लिए भाजपा स्वयं दोषी है।

भाजपा का दोमुंहा रुख: राम जन्मभूमि के व्यापक मसले और विशेषतः ९ नवंबर के प्रस्तावित शिलान्यास पर भारतीय जनता पार्टी का रुख सबसे अधिक दोमुंहा है। एक तरफ जहां भाजपा विश्व हिंदू परिषद का खुला समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी ओर, अपने बंबई अधिवेशन में पारित चुनाव घोषणापत्र में कहती है कि वह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को चुनाव का मुद्दा नहीं बनायेगी। जनता को दिखाने के लिए

साक्षात्कार/अशोक सिंघल

सरकार ६० एकड़ जमीन तथा १४ करोड़ रुपए देने को तैयार है

देश के विभिन्न भागों में भयंकर दंगे हुए हैं और बिहार में तो दंगों ने भीषणतम रूप धारण किया है। इस सांप्रदायिकता के पीछे 'राम शिलापूजन' और ९ नवंबर को राम जन्ममंदिर के प्रस्तावित शिलान्यास को प्रमुख कारण माना जाता है। प्रेक्षकों की धारणा है कि इन दंगों का सर्वाधिक चुनावी लाभ कांग्रेस-इ के खाते में जा रहा है, क्योंकि एक ओर जहां मुस्लिम मतदाता असुरक्षा की भावना के कारण कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं, वहां 'देश की अखंडता को खतरा' का नारा देकर कांग्रेस अन्य मतदाताओं को भी अपनी ओर मोड़ने में लगी है। इस आकलन के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद परोक्ष रूप से कांग्रेस-इ की मदद कर रही है। हमने इस संबंध में अशोक सिंघल का मत जानने के लिए दूसरी बार समय लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बाद में किसी भी सवाल का उत्तर देने से इनकार कर दिया। लेकिन सिंघल ने यह बात मानी है कि सरकार उनको धन और जमीन देकर मदद कर रही है। प्रस्तुत हैं, सिंघल से 'माया' की भेंटवार्ता के अंश:

माया: *देश में सांप्रदायिक दंगों की आग तेजी से फैल रही है, इसके बावजूद आप शिलान्यास पर अड़े हैं। अपने शिलान्यास का कार्यक्रम दो सप्ताह पहले ही क्यों रखा?*

अशोक सिंघल: *हम वहां कोई अशांति करना नहीं चाहेंगे। हिंदू का स्वभाव इतना शांतमय है कि बिना किसी उत्तेजना के अशांति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहा तक सबंध नौ नवंबर का है, यह निर्णय गत वर्ष कुंभ मेले के अवसर पर एक लाख लोगों की प्रतिज्ञा के बाद साधु-संतों ने दवोत्थान एकादशी अर्थात् ९ नवंबर का होना चाहिए।*

चाहिए।

माया: *कितना समय लगेगा मंदिर के निर्माण में?*

सिंघल: *कम-से-कम तीन साल।*

माया: *और धन?*

सिंघल: *आवश्यकता तो कम-से-कम २५ करोड़ की है। पर चुनाव से बाधा आ गयी है। लोग अपना समय-पैसा मंदिर के बजाय राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं।*

माया: *सरकार का क्या रुख है?*

सिंघल: *इस पूरे कार्य में सरकार और नौकरशाही की बहुत गहरी रुचि है। हमारी सरकार से लड़ाई थोड़े ही है। इस समय सरकार ने जन्मस्थान का चार एकड़ स्थान घेर रखा है तथा चारों ओर की ६० एकड़ भूमि अधिकृत कर ली है। यह सारी भूमि सरकार मंदिर निर्माण के लिए दे देगी। मुझे विश्वास है कि कुल मिलाकर ७० एकड़ क्षेत्र मंदिर के लिए मिल सकेगा तथा सरकार १४ करोड़ रुपए कथा मंडप के लिए लगाना चाहती है।*

माया: *पर मंदिर निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ना होगा?*

सिंघल: *हिंदुओं का इतिहास किसी मस्जिद को तोड़ने का नहीं है। हम बाबरी मस्जिद को गिरायेंगे नहीं, बल्कि ससम्मान उठाकर दूसरे स्थान पर रख देंगे। पर बात एक ही है। मस्जिद हटाने के लिए हम शिया नेतृत्व से पूछेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत अच्छे संबंध बनें।*

माया: *क्या मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने से मुस्लिम अलगाववाद नही बढ़ेगा?*

सिंघल: *मुहम्मद अली जिन्ना सोचते थे कि मजहब बदलने से राष्ट्र बदल जाता है। पर मजहब बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता। अलगाववाद को खुलेआम राजनीतिक समर्थन राजीव गांधी जैसे लोगों का मिलता है जो कहते हैं कि उर्दू अलग है। अगर मुसलमानों का कानून अलग है, भाषा अलग है, देवता अलग है, तो अलगाववाद फैलेगा ही। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से अलगाववाद की बात हिंदुओं के खिलाफ 'फियर साइकोसिस' बनाने का प्रयत्न है।*

माया: *राजनीतिक पार्टियों का रवैया आपके प्रति क्या है?*

सिंघल: *उनका एक ही रुख है कि किस तरह वोट मिलें। जिस दल में नास्तिक अधिक हैं वह हमारा विरोधी है और जिस दल में आस्तिक अधिक हैं वह हमारा समर्थन करता है।*

माया: *आपके अनुसार कौन से दल आस्तिक और कौन से नास्तिक।*

सिंघल: *भाजपा पूरी तरह आस्तिकों का दल है। कांग्रेस और जनता दल में भी आस्तिक अधिक हैं। उड़ीसा में तो हमारी एक महिला श्रीमती शांता जनता दल की नेता हैं। पर साम्यवादी दल पूरी तरह नास्तिक हैं, यद्यपि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दुर्गा पूजा समितियों पर कब्जा करके सत्ता में आयी है।*

—अभय अग्रवाल

सार्वजनिक रुख यह है कि राम पर व्यापक आस्था-वाले मामलों को राजनीति का छोटा सवाल नही बनाना चाहिए। पर साथ-ही-साथ भाजपा यह भी कहती है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष में वह पूरी तरह विश्व हिंदू परिषद के साथ है।

कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा का सांप्रदायिक रुख आगामी चुनाव की मजबूरी है, क्योंकि कट्टर हिंदू रुख लेकर ही भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद की शक्ति को अपना वोट बैंक बनाकर रख सकती है। पर भाजपा को भी यह ज्ञात है कि वह संघ और परिषद के कंधे पर चढ़ सत्ता में नही आ सकती तथा पार्टी का राजनीतिक विस्तार आवश्यक है। अतः भाजपा जनतादल जैसी पार्टियों से समझौता कर नये क्षेत्रों में अपने पांव जमाना चाहती है। इस समझौते के लिए आवश्यक है धर्मनिरपेक्ष छवि। अतः भाजपा जनता दल को बहलाने के लिए ऊंचे स्वर में धर्मनिरपेक्षता का मंत्र पढ़ते हुए बजरंग दल के हाथों सांप्रदायिक गदा चलाती है।

जनता दल का अवसरवाद: पर चुनाव पूर्व के भारतीय राजनीतिक पटल की दुखद स्थिति यह है कि काफी हद तक जनता दल ने भी वोटों की खातिर सांप्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिये हैं। अक्तूबर के मध्य में चुनाव घोषित होने तक जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे थे कि वे किसी सांप्रदायिक पार्टी से संबंध नहीं रखेंगे, भले ही उन्हें सत्ता से बाहर रहना पड़े। १७ अक्तूबर को चुनाव घोषित होने से पहले ११ अक्तूबर को एक सभा को संबोधित हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, "हम लोगों का दिमाग साफ है कि अगर सवाल दिल के बंटवारे और वोट के बंटवारे का है, तो हम यह देखेंगे कि दिलों का बंटवारा न हो। देश को बचाये रखना सरकार बनाये रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई चूक चुनाव में हुई, तो पांच साल बाद सुधारी जा सकती है। लेकिन यदि दिलों में दरार पड़ी, तो अनेक पीढ़ियां उसका खमियाजा उठाती हैं।" यही नहीं, जनता दल अध्यक्ष ने विश्व हिंदू परिषद से अपील भी की, "आजादी के आंदोलन के समय जब चौरीचौरा काण्ड हुआ था, तो गांधीजी ने

आंदोलन वापस ले लिया। आज राम जन्मभूमि और शिलापूजन यात्राओं से अगर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है, तो उसे स्थगित कर देना चाहिए।" १७ अक्तूबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बार फिर आशा व्यक्त की कि विश्व हिंदू परिषद शिलान्यास के कार्यक्रम को रोक देगी। पर कुछ ही समय बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कांफ्रेस कर विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपील को ठुकरा दिया और घोषणा की कि शिलान्यास कार्यक्रम पूर्ववत ९ नवंबर को ही होगा। पर इस घोषणा और भाजपा द्वारा इस घोषणा के खुले समर्थन के बावजूद जनता दल भाजपा से चुनावी तालमेल कर रहा है। इसलिए नहीं कि उसे भाजपा की शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि कहीं भाजपा को अलग-थलग करने पर कट्टर हिंदू वोट कांग्रेस की झोली में न चले जायें। बयानबाजी के बावजूद जनता दल अध्यक्ष ने दिल के बंटवारे के ऊपर वोट के बंटवारे को प्राथमिकता दी। सिंह अपना ही वह बयान जानबूझकर भूल गये कि देश को बचाये रखना सरकार बनाये रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सरकारी शह: पर सबसे अधिक खतरनाक राजनीति सत्ता पक्ष (कांग्रेस) की ही है। वह न सिर्फ शिलान्यास की अनुमति दे रही है, बल्कि उसे सरकारी खर्च पर सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। सरकारी सुरक्षा का सीधा-सीधा अर्थ है कि यदि मुसलमानों ने शिलान्यास कार्यक्रम को अथवा बाबरी मस्जिद को टूटने-रुकने से रोका, तो उन्हें न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूलधारियों का सामना करना होगा, बल्कि सशस्त्र पुलिस बलों का भी। मुसलमानों में इस बात से पहले ही भय व्याप्त है कि सरकार ने बाबरी मस्जिद की तथाकथित सुरक्षा के लिए उप्र के बदनाम प्रादेशिक सशस्त्र बल (पीएसी) की ५५ कंपनियां तैनात की हैं जिसके मेरठ दंगों में मुस्लिम विरोधी रवैये पर 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' तक ने प्रतिरोध जारी किया था। यही नहीं, सरकार विश्व हिंदू परिषद को धन तथा भूमि देकर भी सहायता कर रही है। परिषद के कार्यक्रम के अनुसार जिस स्थान पर शिलान्यास किया जाना है, वह प्लाट नं० १६० में पड़ता है, जोकि सरकारी भूमि है। कानूनन जिलाधीश आरएस श्रीवास्तव की अनुमति के बिना उस स्थान पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। शिलान्यास का यह स्थल बाबरी मस्जिद के मुख्य द्वार से १९० फीट दूर है। केंद्र को ज्ञात है कि इस प्लाट पर शिलान्यास होने से सरकार पर आरोप लगेगा कि सरकार विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मदद कर रही है। पर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। यहां तक कि जिलाधीश श्रीवास्तव द्वारा केंद्र को प्रस्तावित कार्यक्रम के पूरे नक्शे भेजे जाने के बावजूद जिलाधीश को ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं कि सरकारी भूमि न हथियायी जाने दी जाये। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल ने तो 'माया' से स्वयं स्वीकारा कि सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए १४ करोड़ रुपए तथा ६० एकड़ भूमि देने की घोषणा की है। यही नहीं, आरएसएस के साप्ताहिक 'आर्गेनाइजर' ने तो यहां तक लिखा है कि स्वय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने को तैयार हैं। साप्ताहिक के अनुसार ऐसा गृहमंत्री बूटा सिंह ने परिषद महामंत्री अशोक सिंघल को बताया था, पर सिंघल नहीं माने। शायद इसलिए कि ऐसा करने पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और वोट सीधे कांग्रेसी झोली में जाते। परिषद कांग्रेस के इशारों पर नाचने को तैयार है, पर उसी सीमा तक कि उसका स्वार्थ सधे और भाजपा जैसे मित्रवत संगठनों को हानि न हो।

कुछ भी हो, जैसे-जैसे शिलान्यास का समय करीब आ रहा है, देश में सांप्रदायिकता का उफान भी आ रहा है। पर्यवेक्षकों का तो यह मानना है कि आगामी चुनाव में बोफोर्स के बाद शिलान्यास की राजनीति से जन्मी सांप्रदायिकता भी अहम मुद्दा होगी। साथ ही इस तरह की अफवाहें भी जोर पकड़ रही हैं कि शिलान्यास का मुद्दा जल्दी ही ऐसा विस्फोटक रूप धारण कर लेगा कि चुनाव टालने तक की नौबत सामने आ जायेगी। फिलहाल सांप्रदायिक उन्माद जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखकर तो इन अफवाहों में भी काफी दम नजर आता है। यदि ऐसा होता है, तो उपर्युक्त तथ्यों तथा सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए यह मान लेना पड़ेगा कि कांग्रेस-इ ने ही अपनी बिगड़ी हुई छवि को ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजना बनायी थी।

—अभय अग्रवाल

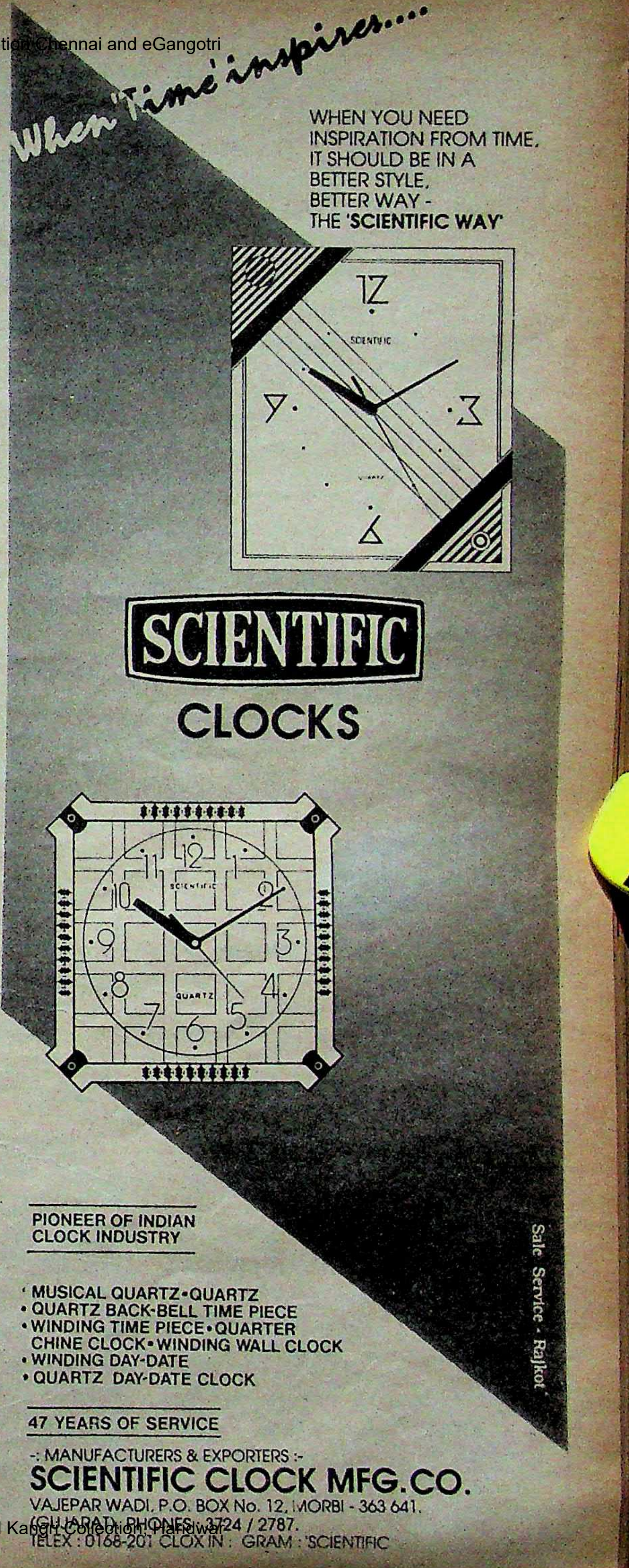
When Time inspires....

WHEN YOU NEED
INSPIRATION FROM TIME,
IT SHOULD BE IN A
BETTER STYLE,
BETTER WAY -
THE 'SCIENTIFIC WAY'

SCIENTIFIC
CLOCKS

PIONEER OF INDIAN
CLOCK INDUSTRY

- MUSICAL QUARTZ•QUARTZ
- QUARTZ BACK-BELL TIME PIECE
- WINDING TIME PIECE•QUARTER CHINE CLOCK•WINDING WALL CLOCK
- WINDING DAY-DATE
- QUARTZ DAY-DATE CLOCK

47 YEARS OF SERVICE

-: MANUFACTURERS & EXPORTERS :-
SCIENTIFIC CLOCK MFG.CO.
VAJEPAR WADI, P.O. BOX No. 12, MORBI - 363 641.
(GUJARAT) PHONES: 3724 / 2787.
TELEX : 0168-201 CLOX IN : GRAM : 'SCIENTIFIC'

Sale Service · Rajkot'

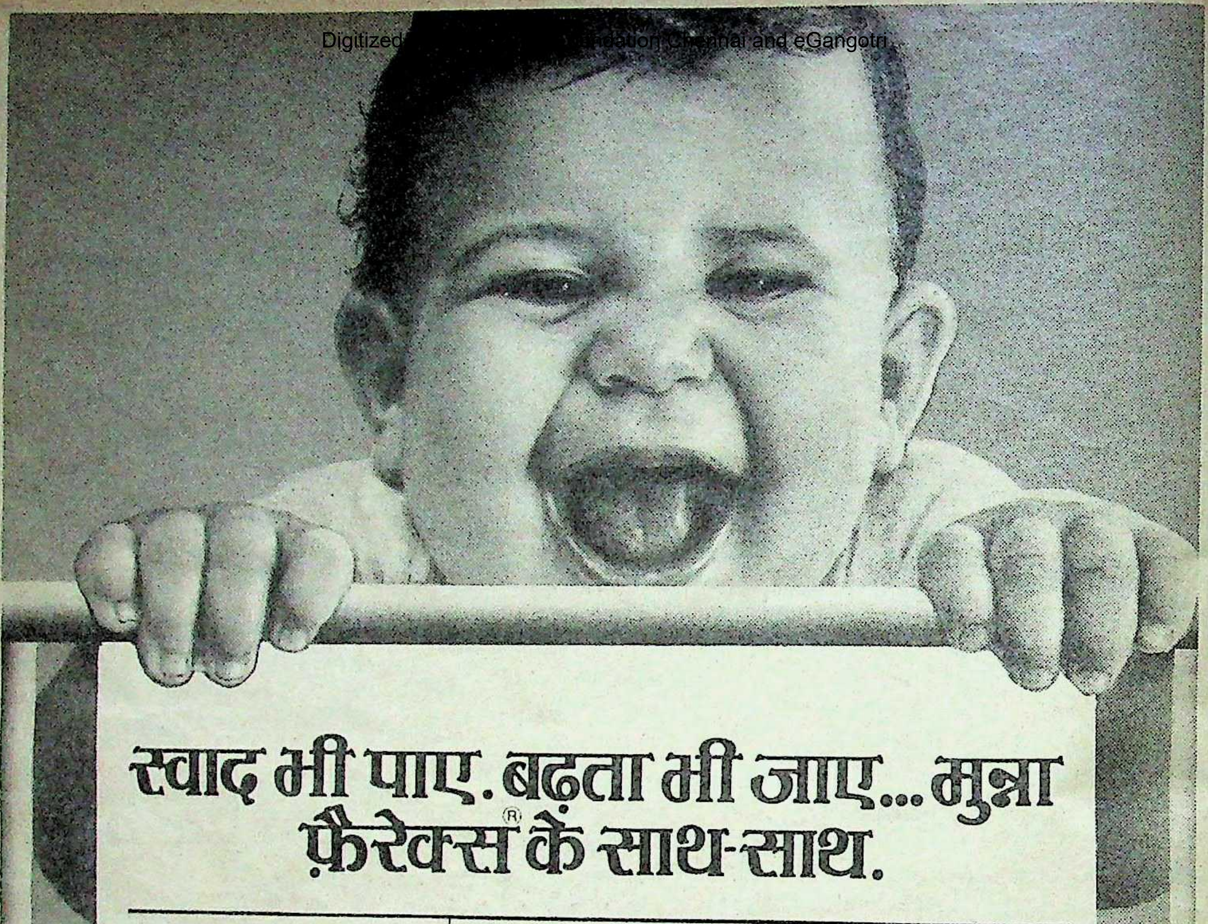

स्वाद भी पाए. बढ़ता भी जाए... मुन्ना फ़ैरेक्स® के साथ-साथ.

अपने शिशु का वज़न व क़द जांचिये *	बेटा		बेटी	
	वज़न	क़द	वज़न	क़द
उम्र ३ महीने तक	५.२ कि.ग्रा.	५९.१ सें.मी.	४.९ कि.ग्रा.	५८.४ सें.मी.
उम्र ६ महीने तक	६.७ कि. ग्रा.	६४.७ सें.मी.	६.१ कि.ग्रा.	६३.७ सें.मी.
उम्र ९ महीने तक	७.३ कि.ग्रा.	६८.२ सें.मी.	६.९ कि.ग्रा.	६७.० सें.मी.
उम्र १२ महीने तक	८.४ कि.ग्रा.	७३.९ सें.मी.	७.८ कि.ग्रा.	७२.५ सें.मी.

* इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किया गया.

भारतीय शिशुओं के लिए यह केवल एक औसत है. अगर आपका डॉक्टर शिशु के विकास से संतुष्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं.

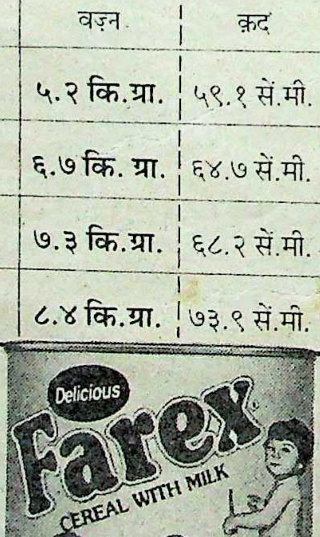

शिशु के चहुमुखी विकास और वृद्धि के लिए उसे पौष्टिकता से भरपूर आहार "फ़ैरेक्स" दीजिये.

फ़ैरेक्स®

शिशु बढ़े.फूले-फले...
जब फ़ैरेक्स मिले

Gx 26 R/2+1 Hin

सांप्रदायिकता के साये में चुनाव

ईंट-से-ईंट बजाने की शह

आम चुनाव से १२ दिन पूर्व अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर की आधारशिला का आयोजन और सरकार की मौन सहमति देश के चुनावी इतिहास की एक ऐसी घटना हो सकती है, जिसकी प्रतिक्रिया में १९४७ का माहौल परिलक्षित हो सकता है। आयोजन से पूर्व ही सांप्रदायिकता के नाग ने फन उठा लिया है। गुजरात के गोधरा, पानलपुर, बड़ौदरा, महाराष्ट्र के नागपुर और शोलापुर, पूर्वी बंबई, कर्नाटक के बंगलौर, उत्तर प्रदेश के बदायूं और अब बिहार के भागलपुर में हुए दंगों के मूल में किसी-न-किसी तरह इस आधारशिला पूजन की घोषणा के बाद से उफनाई सांप्रदायिकता ही हैं। ये दंगे इस बात के सूचक हैं कि यदि आधारशिला का आयोजन चुनाव में व्यस्त राजनीतिक दलों की सियासी चालों से बचकर बिना किसी 'घटना' के संपन्न भी हो गया, तो बाद की प्रतिक्रिया के दुखदायी होने की पूरी आशंका है।

राजनीतिक शह : पहले मंदिर-मस्जिद की यह तकरार 'रामजन्म भूमि' के नाम पर ही बनी समितियों, परिषदों तथा 'बाबरी मस्जिद' के नाम पर गठित हुई कमेटियों के बीच थी। किंतु जब हिंदू-मुस्लिमों के हितचिंतक होने की बात जताने के लिए राजनीति ने इस मुद्दे को गोद' ले लिया, तो इस विवाद का हल गुम हो गया। आधारशिला आयोजन को सरकार की मौन स्वीकृति के पीछे भी उसकी अपनी चुनावी रणनीति है। दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने मुस्लिमों के प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनायी, उससे हिंदुओं का रोष जगजाहिर हुआ। ऐसे विषाक्त माहौल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिये जाने से यह माना जाने लगा कि कांग्रेस ही सांप्रदायिकता की सुलगती आंच में घी उलीचने का काम कर रही है। अचानक भभकी इस आग ने तात्कालिक रूप से बदायूं के सांप्रदायिक सौहार्द को खाक कर डाला। अपने प्रति उपजे हिंदू आक्रोश को इंका ने सियासी तौर पर परखा और उनके मतों को अपने पक्ष में करने के लिए न केवल आधारशिला आयोजन को मौन स्वीकृति दे दी, वरन सुरक्षा व्यवस्था की भी तगड़ी व्यवस्था की है।

जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह हों, कांग्रेस-इ के राजीव गांधी या भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या जनसंघ के बलराज मधोक हों, सबने इस विवाद को सुलझाने के नाम पर मौन बनाये रखने की नीति अपनाकर चुनाव में मतों के विभाजन का लाभ कमाने की सियासी चालें चली हैं। ईश्वर और धर्म को न माननेवाले वामपंथी नेता राजेश्वर राव ने तो पिछले दिनों लखनऊ आकर यहां तक घोषणा कर दी थी कि जब तक वे इस विवाद का हल नहीं निकलवा लेते, अपना डेरा लखनऊ में ही जमाये रखेंगे। यह अलग बात है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद वे अपनी यह कसम तोड़कर अन्य राजनीतिक परिंदों की तरह दिल्ली वापस चले गये। अब वामपंथी दलों द्वारा आधारशिला आयोजन को रोकने के लिए ९ नवंबर को 'अयोध्या मार्च' का ऐलान देशस्तर के बजाय प्रदेश स्तर का हो गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी के मंत्री राम सुमेर यादव के अनुसार, "९ नवंबर को वामपंथी दलों का 'अयोध्या मार्च' निश्चित है, जिसे पार्टी के पोलित-ब्यूरो के सदस्य एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु तथा हरिकिशन सिंह सुरजीत संबोधित करेंगे।" ज्योति बसु आयेंगे या नहीं, यह घोषणा तो नियत तिथि तक हवाई है, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ज्योति बसु ने ही २१ अक्तूबर को कलकत्ता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठककर उन्हें निर्देश दिया कि अयोध्या ले जायी जानेवाली राम शिलाओं (ईंटों) को सुरक्षित तौर पर यहां से जाने की व्यवस्था की जाये।

इस विवाद के दूसरे पक्ष बाबरी मस्जिद-से संबंधित संगठनों के नेता पसोपेश में पड़ गये हैं। मो० आजम खा, जफरयाब जिलानी तथा शहाबुद्दीन जैसे मुखर नेता राजनीति में हैं, लिहाजा चुनाव में मशगूल रहना उनकी मजबूरी है। वैसे इनका ऐलान है कि मुस्लिम संगठनों द्वारा गठित किये गये 'हिफाजती दस्ते' ९ तथा १० नवंबर को अयोध्या पहुंचकर आधारशिला आयोजन का विरोध करेंगे।

सांप्रदायिक तत्व अडिग: दूसरी ओर रामजन्मभूमि से संबद्ध संगठन अयोध्या में विवादित स्थल से कुछ हटकर ९ नवंबर को भूमि पूजन और १० नवंबर को आधारशिला पूजन पर अडिग हैं। हिंदू संगठनों के प्रमुख 'हिंदू जागरण मंच' की युवा शाखा के तेजतर्रार नेता शरद चंद्र मिश्र के इस कथन से आयोजन की अडिगता जाहिर होती है, "९ तथा १० नवंबर को रामजन्मभूमि मदिर निर्माण के भूमि पूजन और आधारशिला पूजन को निर्विघ्न संपन्न कराने की शपथ लेकर मंच के लगभग ५० हजार कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे।" ऐसे में आधारशिला पूजन को निर्विघ्न संपन्न कराने तथा विरोध करनेवाले संगठनों के कार्यकर्ताओं का एक साथ अयोध्या में जमा होना टकराव की नौबत नहीं बनायेगा, यह कहना संभावनाओं की परिधि से भी बाहर है। स्थिति तो यह है कि दोनों संप्रदायों की घोषणाओं ने फैजाबाद और अयोध्यावासियों को ९ तथा १० नवंबर को हादसे की आशंका की गिरफ्त में ला दिया है। अयोध्या से उपजे इस विवाद और बाहरी फिरकापरस्तों के दखल ने यहां के हिंदू-मुस्लिमों का अमन-चैन छीन लिया है। पिछले दो माह से यहां सांप्रदायिक एकता की रणभेरी बजायी जा रही है। २० अक्तूबर को १५ राज्यों से आयी २० हजार महिलाओं ने अयोध्या में सांप्रदायिकता व धर्मांधता के खिलाफ सद्भावना रैली आयोजित की। अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के आह्वान पर इस रैली में भाग लेने आयी प्रबुद्ध महिलाओं में श्रीमती विमला फारूकी, विमला डांग, अजीजा इमाम, डाक्टर हेमलता स्वरूप, पत्रकार डा० मृणाल पांडेय व अरुणा आसफ अली ने नारा दिया, "भारत मां के चार सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई।"

१९ अक्तूबर को दिल्ली में रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति तथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा मनोनीत सर्वोच्च अधिकार संपन्न पांच सदस्यीय समिति द्वारा १० नवंबर को आधारशिला पूजन पर अडिग रहने के ऐलान के बाद २७ अक्तूबर को पुन: लखनऊ में पत्रकार सम्मेलन कर अपनी अडिगता की बात दोहरायी है। इनमें विश्व हिंदू परिषद के महासचिव अशोक सिंघल सहित श्रीशचंद्र दीक्षित, नृत्य गोपालदास, महंत अवैद्यनाथ, स्वामी चिन्मयानंद, आचार्य गिरिराज किशोर, दाऊदयाल खन्ना और विनय कटियार उपस्थित थे। इन नेताओं ने घोषणा की कि यदि आधारशिला पूजन कार्यक्रम में सरकार ने अड़चन लगायी, तो पूरे देश में सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। शिलान्यास की जगह पर उठे विवाद का स्पष्टीकरण देते हुए इन नेताओं ने जानकारी दी, "जहां शिलान्यास होगा, वह स्थान धर्मदास का है। पहले का स्थान अविराम दास का था। उन्होंने रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलने के बाद रामनवमी को यह स्थान रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति को दान में दिया था। इन नेताओं का कहना था कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे आधारशिला पूजन कार्यक्रम का हाथ नहीं है। कुछ सियासी किस्म के फिरकापरस्त हिंदू-मुस्लिमों को आपस में लड़ा रहे हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है। इन नेताओं का तर्क था कि आम मुस्लिम राम मंदिर निर्माण का विरोधी नहीं है, यही वजह है कि हमें उनका भी सहयोग मिल रहा है। लखनऊ के दरगाह हजरत अब्बास रोड के शिया मुसलमानों ने मंदिर निर्माण के ९५१ ईंटों के १०० रुपए दिये हैं। इसके पूर्व खुमैनी अरबी दारुल उलूम द्वारा १२० और हिंदू-शिया संगठन द्वारा ९५० ईंटे राम मंदिर निर्माण हेतु दान दी गयी हैं।

कुल मिलाकर ९ तथा १० नवंबर को यदि आधारशिला पूजन टाला नहीं गया, तो किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। आधारशिला पूजन के बाद मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से शुरू होगा। इस तरह इस विवाद के जरिये साप्रदायिकता का सौहार्द के विरुद्ध विषवमन जारी रहेगा। ऐसे समय में सरकार का सचेत रहना और लोगों का साप्रदायिक सौहार्द के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है, तभी सांप्रदायिकता की मार से कराहती मानवता को आगे के अंदेशा से उबारा जा सकता है।

—सुरेश द्विवेदी

ऐसी भी मिसालें !

रामजन्म भूमि तथा बाबरी मस्जिद विवाद के चलते आज की बौखलायी सांप्रदायिकता कभी इतनी शांत थी कि आपसी सौहार्द ने उसे तेवर बदलने का मौका ही नहीं दिया था। लखनऊ के इतिहास के पन्ने पलटे जायें, तो सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी अनेक मिसालें मिलती हैं, जिन्हें आज भी देखा-परखा जा सकता है।

रामजन्म भूमि चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, पर यह सच है कि लखनऊ में अलीगंज स्थित हनुमानजी का विशाल मंदिर, नवाब सआदत अली खां की मां जनाब आलिया ने बनवाया था। इसका गवाह इतिहास तो है ही, साथ में मंदिर के शिखर पर मुगल सल्तनत के कौमी निशान 'दूज के चांद' को भी देखा जा सकता है।

इसके विपरीत लखनऊ की मशहूर शाहदरा मस्जिद का निर्माण किसी मुसलमान ने नहीं, वरन् एक हिंदू राजा ठाकुर देव ने कराया था। १५वीं सदी के आरंभ में यह निर्माण तब हुआ, जब राजा के दो बहादुर पठान सिपहसालार एक युद्ध जीतकर आये थे।

अवध के नवाब आसफुद्दौला ने चिनहट वाली मस्जिद और सराय शेख का शिव मंदिर साथ-साथ बनवाया था। इस मंदिर की देखरेख के लिए नवाब ने २०० एकड़ भूमि बतौर जागीर प्रदान की थी, जहां एक ताम्रपत्र पर फारसी में लिखा हुआ था, "नवाब का फरमान है कि यह संपत्ति भगवान की पूजा के निमित्त है और यह वसीयत उसी के लिए है।"

लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित बाबा गोमती दास की समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही कराया था। जबकि नवाब के खासमखास नायब राजा झाड़मल ने 'शिया बैतुलमाल' को स्वयं खड़े होकर बनवाया। इसे आज भी परखा जा सकता है, क्योंकि बाबा गोमती दास मंदिर की बनावट किसी मुगल बारादरी जैसी है। वहीं दूसरी ओर 'शिया बैतुलमाल' के दरवाजों में राजपूती तोरणों की स्पष्ट झलक मिलती है।

नवाबी दौर में वसंत पंचमी के दिन गोमती तट पर हजारों लोग उत्सव मनाते थे। हिंदुओं के इस त्यौहार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, शाही घराने के लोग किस प्रकार हिस्सा लेते थे, इसका अंदाजा आज हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी में लगी एक तस्वीर से लगाया जा सकता है। इस तस्वीर में अवध के अंतिम बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को अपनी कई बेगमों के साथ वसंती कपड़े पहने उत्सव में शामिल दिखाया गया है।

तस्वीर में नसीरुद्दीन के साथ उनकी मुंहलगी धनिया नामक महरी भी खड़ी है। धनिया के लिए बादशाह ने अलीगंज स्थित महादेव के मंदिर के मार्ग में पड़नेवाले नाले का पुल बनवाया था। बादशाह की इस कृतज्ञता को चुकता करने के लिए धनिया ने मौलवीगंज में एक खूबसूरत मस्जिद बनवायी। उसने यह काम इनाम में मिलनेवाली रकम से किया।

बहरहाल, सांप्रदायिक सौहार्द के ऐसे धर्मनिरपेक्ष इतिहास को संजोने वाले देश में आज अयोध्या का एक विवादास्पद स्थल राजनीतिक दलों की स्वार्थसिद्धि का जरिया बन गया है और बेगुनाह लोग इस विवाद से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में देश का इतिहास तो कलंकित हो ही रहा है, साथ में अमन और शांति भी दांव पर लग गयी है।

—राजीव सक्सेना

पम्प चले तो फ़सल फले
पम्प बंद तो काम मंद

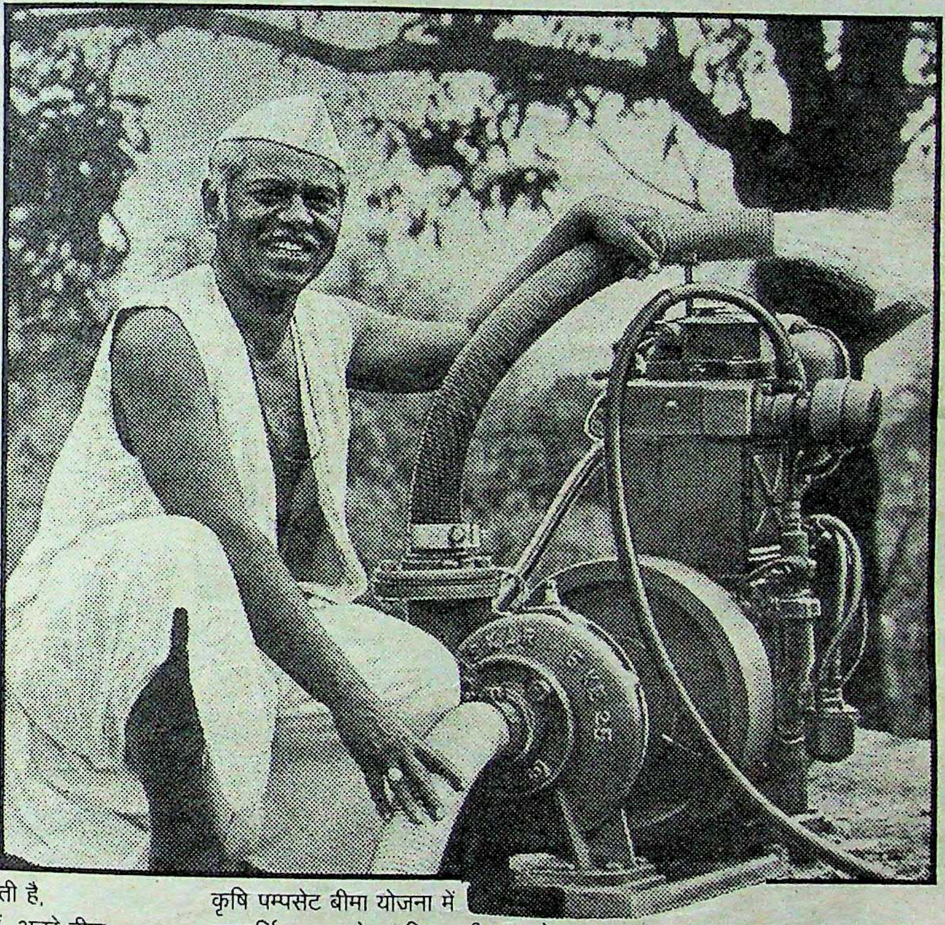

किसान की जान
उसकी फ़सल में बसती है,
तो फ़सल की पानी में अच्छे बीज,
अच्छी खाद और कमरतोड़ मेहनत
सब बेकार हो जाएं अगर फ़सल को
समय पर पूरा पानी न मिले.

खड़ी फ़सल को पानी की ज़रूरत हो,
कुएं में पानी भी हो और ऐसे में
पम्प जल जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए
या चोरी हो जाए तो किसान तो
बरबाद हो जाए.

ऐसी मुसीबत में किसान को सहारा देता है
न्यू इन्डिया का कृषि पम्पसेट बीमा.

कृषि पम्पसेट बीमा योजना में
सबमर्सिबल पम्पसेट सहित सभी तरह के
पम्पसेटों का बीमा किया जाता है.

कृषि पम्पसेट बीमे की दर : मोटर की
हॉर्स पावर के हिसाब से कम से कम
50 रुपये सालाना.

न्यू इन्डिया के 1000 से भी अधिक कार्यालय
देशभर में फैले हुए हैं.

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीक के
कार्यालय में पधारें या एजेंट से मिलें.
आपकी सेवा के लिए दूरदराज़ के गांवों में भी
न्यू इन्डिया के ग्रामीण प्रतिनिधि तैनात हैं.

R K SWAMY/NIA/4294/HN-A

कृषि पम्पसेट बीमे के लिए

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कंपनी

हर मुसीबत में आपका सहारा

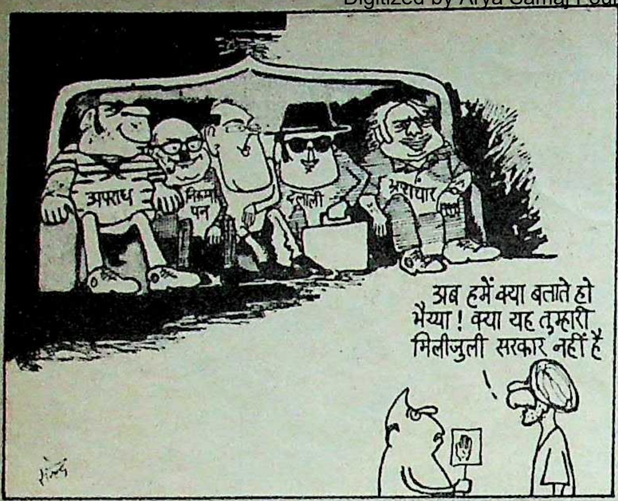
अपराध
निकम्मापन
दलाली
भ्रष्टाचार
अब हमें क्या बताते हो भैया! क्या यह तुम्हारी मिलीजुली सरकार नहीं है

'जनसत्ता' के सौजन्य से

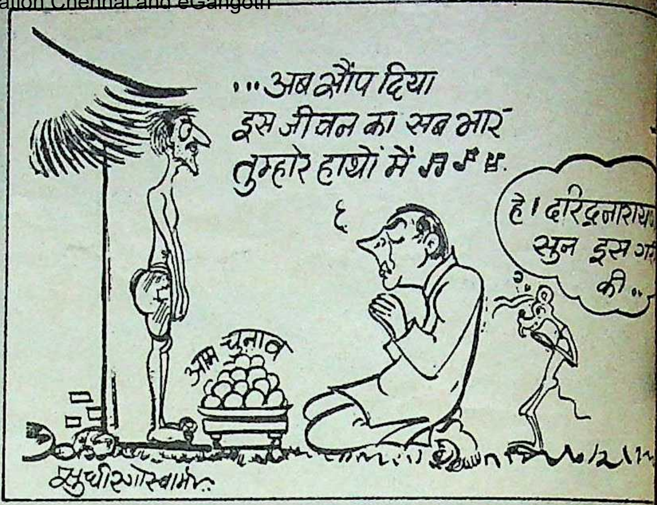
...अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में ♫♪♫
हे! दरिद्रनारायण सुन इस ग... की..
आम चुनाव
सुधीर गोस्वामी

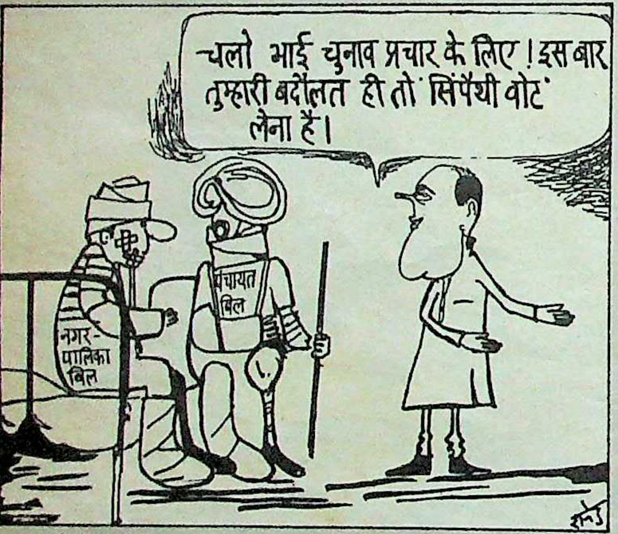
चलो भाई चुनाव प्रचार के लिए! इस बार तुम्हारी बदौलत ही तो सिंपैथी वोट लेना है।
नगर-पालिका बिल
पंचायत बिल

'जनसत्ता' के सौजन्य से

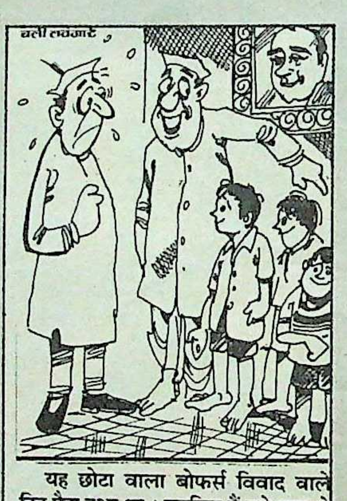

यह छोटा वाला बोफर्स विवाद वाले दिन पैदा हुआ था। इसलिए मैं इसे प्यार से 'बोफर्स' कहता हूं।

'जनसत्ता' के सौजन्य से

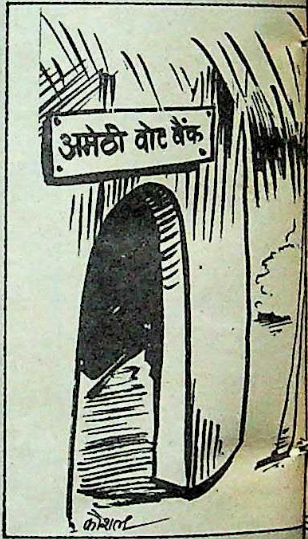
अमेठी वोट बैंक
कौशल

'अमर उजाला' के सौजन्य से

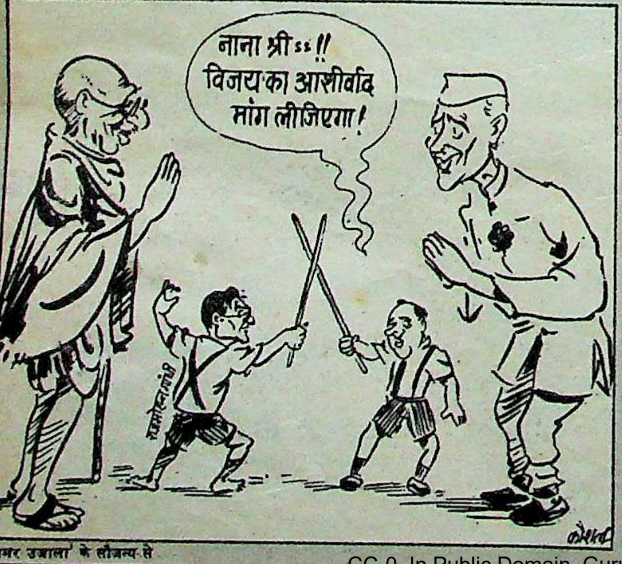
नाना श्री ऽऽ!! विजय का आशीर्वाद मांग लीजिएगा!
राजमोहन गांधी
कौशल

'अमर उजाला' के सौजन्य से

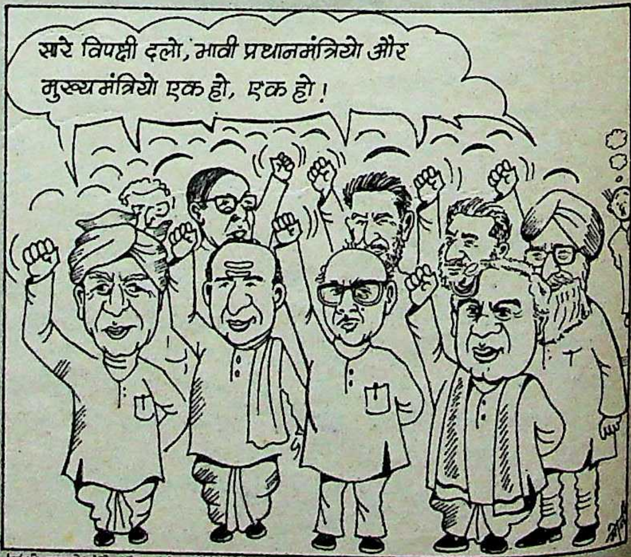
सारे विपक्षी दलो, भावी प्रधानमंत्रियो और मुख्य मंत्रियो एक हो, एक हो!

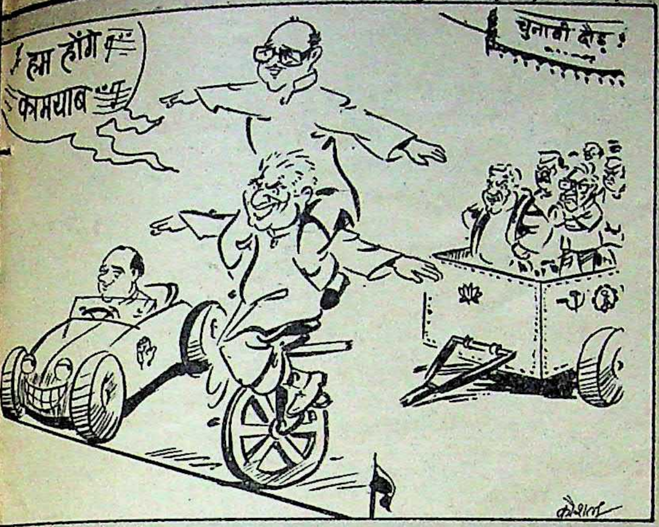
हम होंगे कामयाब
चुनावी दौड़!
कौशल

'अमर उजाला' के सौजन्य से

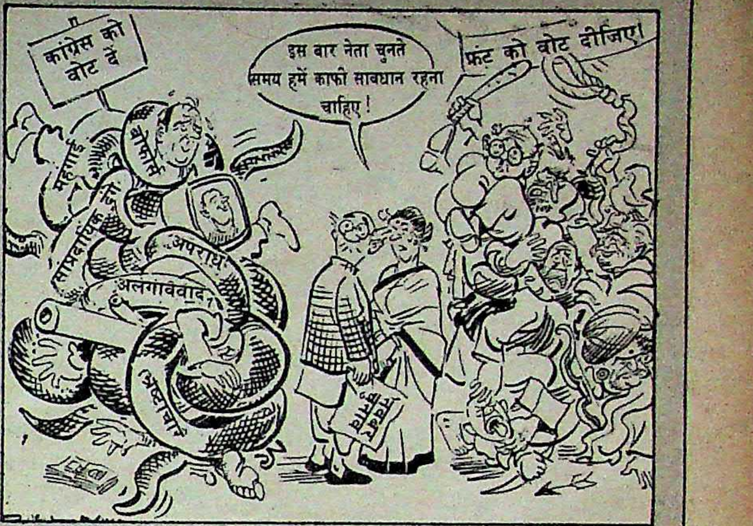
कांग्रेस को वोट दें
इस बार नेता चुनते समय हमें काफी सावधान रहना चाहिए!
फ्रंट को वोट दीजिए!
महंगाई
बोफोर्स
साम्प्रदायिक दंगे
अपराध
अलगाववाद
भ्रष्टाचार

कार्टून: आरके लक्ष्मण

'टाइम्स आफ इंडिया' के सौजन्य से

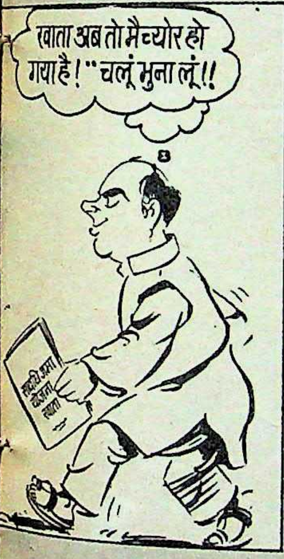
खाता अब तो मैच्योर हो गया है! "चलूं भुना लूं!!

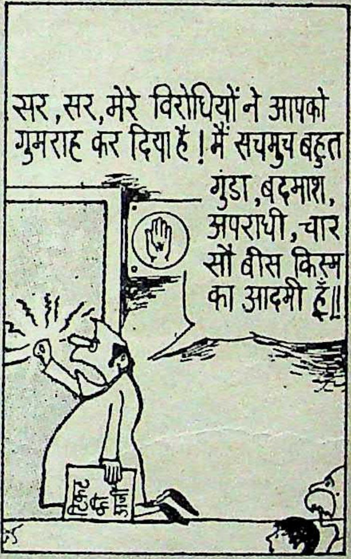
सर, सर, मेरे विरोधियों ने आपको गुमराह कर दिया है! मैं सचमुच बहुत गुंडा, बदमाश, अपराधी, चार सौ बीस किस्म का आदमी हूं!!

'जनसत्ता' के सौजन्य से

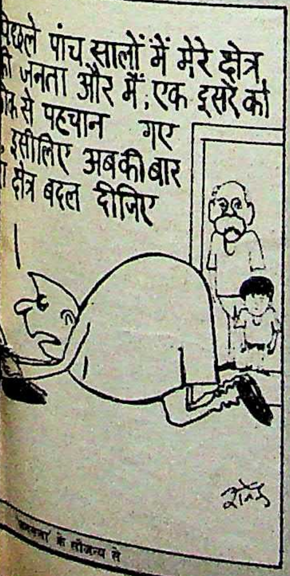
छले पांच सालों में मेरे क्षेत्र
जनता और मैं, एक दूसरे को
से पहचान गए
इसीलिए अबकी बार
क्षेत्र बदल दीजिए

'जनसत्ता' के सौजन्य से

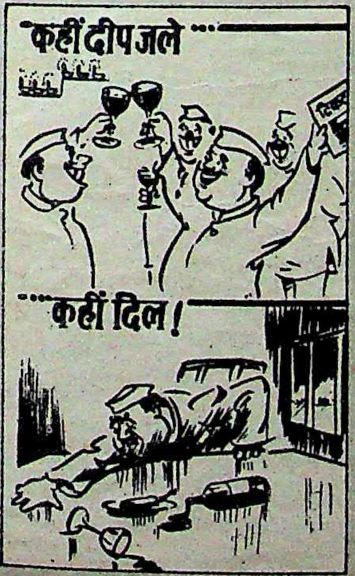
कहीं दीप जले...
...कहीं दिल!

विज्ञापन कांग्रेस-इ का प्रचार विपक्ष का

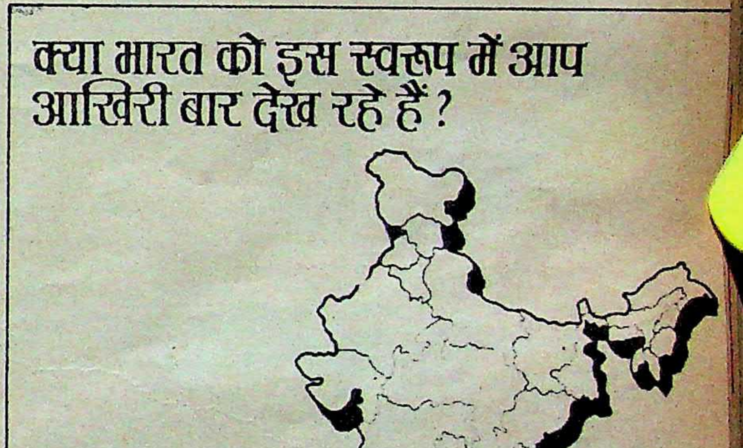

क्या भारत को इस स्वरूप में आप आखिरी बार देख रहे हैं?

विदेशियों को बेच दिया जाएगा देसी दलालों द्वारा

मेरी हर धड़कन भारत के लिये है!

लखनऊ से प्रकाशित 'नवभारत टाइम्स' में
कांग्रेस-इ के विज्ञापन में किसी व्यक्ति ने फोन करके यह पंक्ति जुड़वा दी:

'विदेशियों को बेच दिया जायेगा दलालों द्वारा'

'तूफान' पर कहर

१ नवंबर को ८ डाउन तूफान एक्सप्रेस ट्रेन रात ४ बजकर ५ मिनट पर जब मुगलसराय (वाराणसी) स्टेशन से छूटी, तो सर्द रात का कोहरा फैला हुआ था। ट्रेन की आगे की बोगियों में खचाखच भीड़ थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन की छतों पर भी लोग सवार थे। १६ बोगियोंवाली ट्रेन ९० किमी० प्रति घंटे की रफ्तार से जब कछवां और सकलडीहा रेलवे स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी, तभी ४ बजकर १३ मिनट पर तेनवट गांव के पास इस यात्री गाड़ी की १० बोगियां पटरी से उतर कर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इनमें से ४ बोगियां तो बुरी तरह से चकनाचूर हो गयीं। मुसीबत में फंसे यात्रियों की चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाजों ने तेनवट गांव की रात की शांति और गहरी निद्रा में सो रहे गांववासियों को झकझोर दिया। सर्द रात के कुहासे को भेदती गांववालों की भीड़ अपने घरों से घटनास्थल की ओर बढ़ चली और अपनी जान की परवाह किये बिना गांववाले क्षतिग्रस्त बोगियों में फंसे यात्रियों को बचाने के काम में जुट गये थे। ट्रेन की बोगिया पटरी से उतरने के बाद बिजली के खंभों से भी टकरायी थी, जिससे तार जमीन पर बिखर गये थे और करंट फैल गया था।

हर ट्रेन दुर्घटना की तरह इस दुर्घटना में भी मरनेवालों की संख्या अधिक है, पर हर बार की तरह रेल विभाग मृतकों की संख्या कम बता रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरनेवालों की संख्या २५० से कम नहीं है, पर रेल विभाग ५० लोगों के मरने की पुष्टि करता है। इस हादसे में बिहार सेना पुलिस के ९ जवान भी मौत की भेंट चढ़ गये। घायलों की सख्या ६०० से कम नहीं है। पर रेल विभाग इनकी भी संख्या १०० के आसपास आंक रहा है। यह बात इसलिए लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि ४ बोगियां तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं और हर बोगी में कम-से-कम ८०-८० लोगों के होने का अनुमान है।

यह दुर्घटना भी रेल विभाग की लापरवाही से हुई। बताया गया कि मुख्य लाइन में गड़बड़ी होने के कारण दुर्घटना के दो दिन पहले से अप तथा डाउन सभी ट्रेनें लूप लाइन से पास की जा रही थीं। लूप लाइन से जब गाड़ियां पास करवायी जाती हैं, तो 'काशन सिगनल' का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्रेन की रफ्तार कम रहे। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रेन को 'काशन सिगनल' देने के बजाय सीधा सिगनल दे दिया गया, नतीजतन ट्रेन ड्राइवर ने रफ्तार कम नहीं की। दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात का पता चलाने के लिए रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच चल रही है। फिलहाल सरकार ने मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए और घायलों को विभिन्न राशि में मुआवजा देने की रस्म अदा कर दी है। घटनास्थल पर वैसे तो रेल राज्यमंत्री माधव राव सिंधिया शीघ्र ही पहुंच गये थे—लेकिन उनके पहुंचने के पूर्व और बाद भी राहत का काम मंद गति से ही चल रहा था। ट्रेनों में फंसे घायलों और मृतकों को निकालने का काम घटना के अट्ठारह घंटे बाद भी पूरा नहीं हुआ था।

—दिनेश दीनू

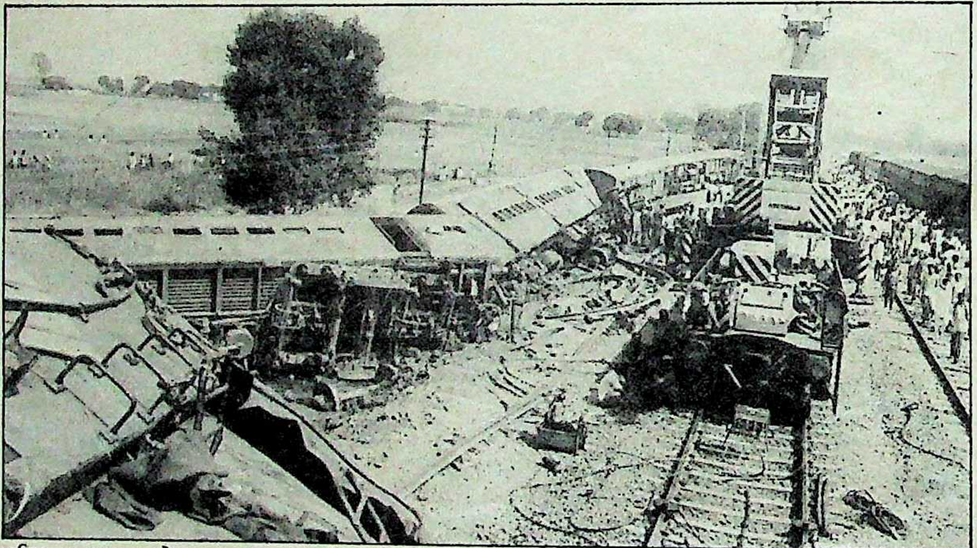

अभिशप्त तूफान मेल: मुगलसराय के पास दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन

छाया: क्लाउन

यात्रा जो अंतिम बन गयी: यात्रियों के शव

छाया: क्लाउन

चुनावी मोर्चे—एक नजर में

नौवीं लोकसभा के लिए असम (१४ सीटें) को छोड़कर २४ प्रांतों और केंद्र शासित ७ प्रदेशों में होनेवाले आम चुनाव में इस बार कुल ४९८६४७७८६ मतदाता (नये युवा मतदाता—३५६७७८१५) ५९६००० मतदान केंद्रों (१९८४ में ४९२०००) पर २२, २४ व २६ नवंबर को मतदान करके लोकसभा के ५२९ सदस्यों का चुनाव करेंगे। (१९८४ में ३८ करोड़ ९० लाख मतदाता थे)। १९८४ के आमचुनाव पर भारत सरकार का ८८ करोड़ रुपए खर्च आया था, लेकिन इस बार कागज आदि की कीमतों के बढ़ जाने के कारण अनुमान है कि इस आमचुनाव में १६६ करोड़ रुपए का खर्च आयेगा। लेकिन अकेले कांग्रेस-इ अपने चुनाव प्रचार पर ३०० करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक अनुमान के अनुसार सभी पार्टियों और प्रत्याशियों के कुल खर्चों को जोड़ा जाये, तो इस आमचुनाव में इस देश के एक हजार करोड़ रुपए स्वाहा हो जायेंगे।

लोकसभा के साथ ही पांच प्रांतों—उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी २२, २४ और २६ नवंबर को होंगे।

१९८४ के आम चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत ५९ राजनीतिक दल मैदान में उतरे थे, इस बार इनकी संख्या बढ़कर ८२ हो गयी है। चार पार्टियों के विलय से बनी नयी पार्टी जनता दल ने इस बार कांग्रेस-इ का विकल्प बनने का मंसूबा लिये छह तीलियों के चक्र के चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है।

राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है, जिसका चुनाव चिन्ह—'गेंहू जौ की बाली के साथ हंसिया' आज तक नहीं बदला है। कांग्रेस का १९५२ में चुनाव चिन्ह 'दो बैलों की जोड़ी' था, १९७१ में 'गाय बछड़ा' तथा १९८० में फिर बदलकर 'हाथ का पंजा' हो गया। १९७१ तक भाजपा जनसंघ थी और उसका चुनाव चिन्ह था, 'दीपक' जो १९८४ में बदलकर 'कमल का फूल' हो गया।

कांग्रेस ने संसद की ५२९ सीटों के लिए होनेवाले चुनाव में ५०९ सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये हैं तथा शेष १९ सीटें अपने सहयोगी दलों अन्नाद्रमुक (११), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (३), नेशनल कांफ्रेंस (३), यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (१), और केरल कांग्रेस मणिगुट (१) में बांट दी है तथा दार्जिलिंग की सीट पर अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। १९८४ में कांग्रेस ने ५०७ उम्मीदवार खड़े किये थे। इस बार चुनाव की पूर्व संध्या में नगालैंड के तीसरे बड़े राजनीतिक दल नगा पीपुल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया।

प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने तीस प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की थी, क्योंकि ४९.८ करोड़ मतदाताओं में ४८ प्रतिशत महिला मतदाता हैं, लेकिन इन दलों द्वारा जारी सूचियों के अनुसार कांग्रेस ने १०.८ प्रतिशत, भाजपा ने ५.५ प्रतिशत, जनता दल ने २.३ प्रतिशत तथा वामपंथी दलों ने ४.७ प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिये। कांग्रेस के कुल ५०९ प्रत्याशियों में से महिला प्रत्याशियों की संख्या—५३ है।

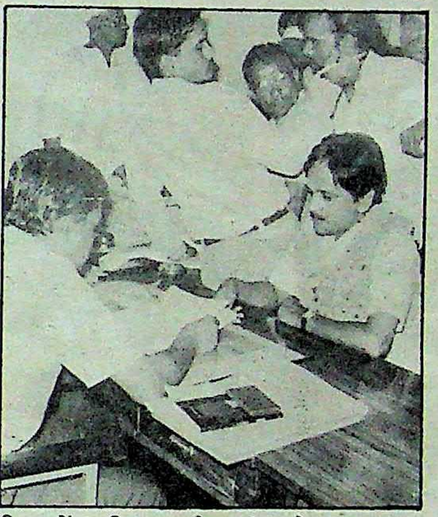

विपक्ष में: अनिल शास्त्री नामांकन के समय

१९८४ में ९४ प्रतिशत (३८ में ३६) और १९८० में ६२ प्रतिशत (३२ में २०) कांग्रेस महिला प्रत्याशी विजयी रही थीं, जबकि १९८४ व १९८० में विपक्ष की क्रमशः कुल २९ व ४९ महिला प्रत्याशियों में से क्रमशः २३ व ३९ महिला प्रत्याशी चुनाव हार गयी थीं। इस बार पूरे देश में महाराष्ट्र के राजापुर तथा मध्य प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों (रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंह, कांकेर, बस्तर रायपुर, बालाघाट और मंडला) में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।

देश की ५२९ लोकसभा सीटों के लिए २४ राज्यों और ७ केंद्रशासित क्षेत्रों में ६९०० प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। १९८४ में कुल मिलाकर ५४९३ नामांकन पत्र दाखिल हुए थे।

अनेक प्रांतों में टिकट न मिलने से पक्ष-विपक्ष के अनेक नेता बागी हो गये। गोवा के चार प्रमुख कांग्रेसियों ने पार्टी से इस्तीफे दे दिये। गुजरात के वरिष्ठ मंत्री विजय दास महंत ने जूनागढ़ से तीसरी बार कांग्रेस का टिकट न मिलने से मंत्रिमंडल से ही त्यागपत्र दे दिया। रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत को नैनीताल से लोकसभा का टिकट न दिये जाने के कारण उन्होंने कहीं से भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तो उत्तर प्रदेश के वनमंत्री अजीत प्रताप सिंह ने इस कारण चुनाव न लड़ने का फैसला किया, क्योंकि इन्हें पट्टी की उस विधानसभा सीट का टिकट दे दिया गया था, जहां से उनके मुकाबले खुद उनके पुत्र अभय प्रताप सिंह जनता दल के प्रत्याशी के रूप में—चुनाव लड़ रहे हैं। पिता ने पुत्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प० बंगाल के मिदनापुर संसदीय क्षेत्र में वामपंथी मोरचे के प्रत्याशी मौजूदा सांसद नारायण चौबे का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस-इ ने जब उनकी ही पत्नी श्रीमती गौरी चौबे को टिकट दिया, तो वे सहर्ष तैयार हो गयीं, लेकिन बिहार के वैशाली संसदीय क्षेत्र से जद प्रत्याशी उषा सिंह के खिलाफ उनके पति वीरेंद्र सिंह यद्यपि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे पत्नी की प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस-प्रत्याशी किशोरी सिन्हा के पाले में नामांकन पत्र भरने के दिन ही चले गये।

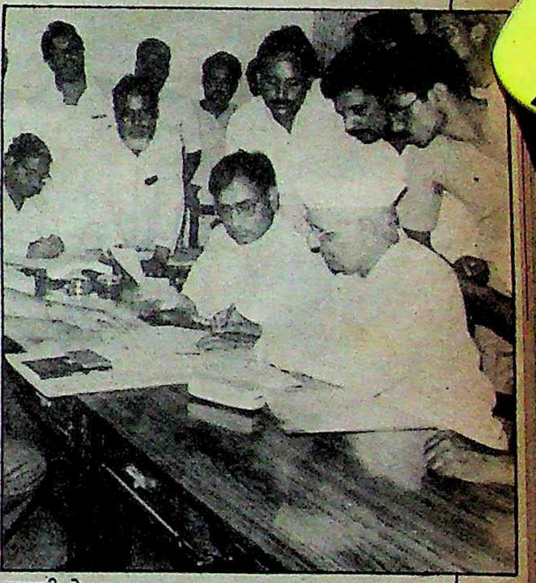

शास्त्री से मुकाबला: श्यामलाल यादव छाया: क्लाउन

आंध्र प्रदेश के पांच भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जे वेंगलराव खम्माम व के विजय भास्कर रेड्डी करनूल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस-इ के प्रत्याशी हैं। एम चेन्नारेड्डी सनतनगर तथा एन भास्कर राव ने तेनाली विधानसभा से नामांकन पत्र भरा है।

सुरक्षाकर्मियों ने ही श्रीमती गांधी की हत्या कर दी थी, तो कांग्रेस सरकारों के लिए १९७७ से ही रक्षामंत्री सिरदर्द रहे हैं। १९७७ में रक्षामंत्री

जगजीवन राम ने ऐन चुनावों के वक्त कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। १९८७ में कांग्रेस-इ से अलग होने के पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रक्षामंत्री थे और इस बार टिकट वितरण के समय कांग्रेस के जिस नेता ने नाराज होकर कहीं से भी लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की वे कृष्ण चंद्र पंत भी राजीव सरकार में रक्षामंत्री हैं।

एक अवसर ऐसा भी आया जब जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना नामांकन पत्र भरने के लिए आत्मदाह तक की धमकी देनी पड़ी। ३० अक्तूबर को सवा छह बजे वायुदूत का विमान उन्हें लेकर दिल्ली से कानपुर के लिए उड़ा ही था कि बम की आशंका से उसे वापस बुला लिया गया।

हरियाणा सरकार ने जब अपना विमान देने की पेशकश की, तो उसे हवाई अड्डे के अधिकारियों ने मंजूर नहीं किया। तब वीपी सिंह की आत्मदाह की धमकी के बाद साढ़े ग्यारह बजे वायुदूत का विमान उन्हें लेकर १२ बजकर, ४५ मिनट पर कानपुर पहुंचा, वहां से ७५ किलोमीटर दूर फतहपुर पहुंचकर जब वीपी सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा, तो नामांकन का समय समाप्त होने में सिर्फ २० मिनट का समय बचा था।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस

लोकसभा चुनाव	कुल सीटें	कांग्रेस ने जीती	मतदान का प्रतिशत	कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत
१९५२	४८९	३६४	४५.७७	४४.९९
१९५७	४९४	३७१	४७.७४	४७.७८
१९६२	४९४	३६१	५५.४२	४४.७३
१९६७	५२२	२७९	६१.३३	४०.७२
१९७१	५२२	३५२	५५.२२	४३.७२
१९७७	५४२	१५३	६०.५४	३४.५४
१९८०	५४२	३५२	५७.००	४२.५६
१९८४	५०८	४०१	६५.०४	४८.१०

जालौर (राजस्थान) में बूटा सिंह के खिलाफ पर्चा भरने के लिए हरियाणा सरकार के विमान से दिल्ली पहुंचे जद नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चांदराम को आगे उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली जिसके कारण वे जालौर से अपना नामांकन पत्र नहीं भर सके, लेकिन उनसे पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरवा दिया गया।

इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने बिहार के किशनगंज क्षेत्र से कांग्रेस-इ के एमजे अकबर के खिलाफ नामांकन पत्र भरा था, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ियों के कारण उनका नामांकन यहां से रद्द हो सकता है, तो उन्होंने बंगलोर उत्तरी संसदीय क्षेत्र से भी नामांकन भर दिया। अब वे बंगलोर से ही चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद से भी उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन वहां से नाम वापस ले लिया।

इंदिरा गांधी हत्याकांड का एक अभियुक्त अतिंदरपाल सिंह पटियाला लोकसभा क्षेत्र से अकाली दल (मान) की ओर से चुनाव लड़ रहा है। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के पिता सुच्चासिंह भी भंटिडा से अकाली दल (मान) के प्रत्याशी हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दो पुत्र हरिकृष्ण शास्त्री और सुनील शास्त्री कांग्रेस में हैं तो उनके तीसरे पुत्र अनिल शास्त्री को जनता दल राजनीति में खींच लाया है तथा उन्हें बनारस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के श्याम लाल यादव के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा है।

नौवीं लोकसभा के लिए होनेवाले आम चुनाव में कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं—जो वहां खड़े नामचीन प्रत्याशियों के कारण पूरे देश की दिलचस्पी का केंद्र बन गये हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज अपना भाग्य आमजा रहे हैं—वे हैं—बिहार-अब्दुल गफूर (सीवान), रामलखन यादव (बाढ़), एमजे अकबर (किशनगंज), तारिक अनवर (कटिहार), भगवत झा आजाद (भागलपुर), केके तिवारी (बक्सर), मीरा कुमार (सासाराम), शंकर दयाल सिंह (धनबाद), गुजरात—दिग्विजय सिंह (सुरेंद्रनगर), योगेंद्र मकवाना (पाटन), अहमद पटेल (बड़ौच) हरियाणा—भजनलाल (फरीदाबाद), बंशीलाल (भिवानी), हिमाचल प्रदेश—सुखराम (मंडी), जम्मू-कश्मीर—धर्मपाल (उधमपुर), कर्नाटक—जी गावडा (माण्डया), जनार्दन पुजारी (मंगलौर), आस्कर फर्नांडिस (उडुपी), वी शंकरानंद (चिक्कोडी), मध्य प्रदेश—माधव राव सिंधिया (ग्वालियर), कमलनाथ (छिंदवाड़ा), पीसी सेठी (इंदौर), महाराष्ट्र—एआर अंतुले (कोलाबा), सुनील दत्त (बंबई उत्तर-पूर्व), पीवी नरसिम्हाराव (रामटेक), वसंत साठे (वर्धा), वीएन गाडगिल (पूना), उडीसा—केपी सिंहदेव (देकानाल), जयंती पटनायक (कटक), पंजाब—अजीत सिंह मान (तरनतारन), राजस्थान—बलराम झाखड़ (सीकर), राजेश पायलट (भरतपुर), बूटा सिंह (जालौर), अशोक गहलोत (जोधपुर), राम निवास मिर्धा (नागगौर), तमिलनाडु—पी चिदंबरम (शिवागंगा), उत्तर प्रदेश—राजीव गांधी (अमेठी), दिनेश सिंह (प्रतापगढ़), कल्पनाथ राय (घोसी), हरिकृष्ण शास्त्री (फतेहपुर), रामनरेश यादव (बदायूं), शीला दीक्षित (कन्नौज), मोहसिना किदवई (मेरठ), प० बंगाल—अबू गनी खान चौधरी (मालदा), प्रियरंजन दासमुंशी (हावड़ा)।

दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं—एचकेएल भगत (पूर्वी दिल्ली), जगदीश टाइटलर (सदर बाजार) और धर्मदास शास्त्री (करोलबाग) को कड़े मुकाबले का सामना करना है, तो नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस की श्रीमती मोहिनी गिरी (वीवी गिरी की पुत्री) के मुकाबले अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

जनता दल के जिन प्रमुख नेताओं के चुनाव परिणाम जान लेने को पूरा देश उत्सुक है, वे हैं—उत्तर प्रदेश—राजमोहन गांधी (अमेठी), विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर), आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच), अरुण नेहरू (बिल्हौर), अजीत सिंह (बागपत), चंद्रशेखर (बलिया), पंजाब—देवीलाल (फिरोजपुर, पंजाब-सीकर-राजस्थान), मध्य प्रदेश—विद्याचरण शुक्ल (महासमुंद), महाराष्ट्र—मधु दंडवते (बंबई उत्तर-मध्य), मृणाल गोरे (बंबई उत्तरी)।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल ६६ प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारे हैं, जिनमें से ३१ अकेले पं० बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के नरेश चंद्र चतुर्वेदी के मुकाबले माकपा ने उमराव जान फिल्म की नायिका सुभाषिनी अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाकपा के ५४ प्रत्याशी मैदान में हैं।

अटलबिहारी वाजपेयी; राज बब्बर, अमिताभ बच्चन, केसी पंत, एनटी रामाराव, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा आदि ऐसे चर्चित नाम हैं जो नौवीं लोकसभा के चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कांसीराम खुद नयी दिल्ली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही ३३० संसदीय क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं।

—संयोजन : विनोद मिश्र

राष्ट्र–
(बंबई
मटेक),
(पूना),
जयती
ह मान
झाखड़
टा सिंह
), राम
ाड़ु–पी
-राजीव
पगढ़),
शास्त्री
, शीला
मेरठ),
लदा),

चकेएल
ाइटलर
शास्त्री
करना
अध्यक्ष
मोहिनी
अपना

चुनाव
क है, वे
मेठी),
आरिफ
नेहरू
द्रशेखर
ोजपुर,
विद्या-
दंडवते
(बंबई

न ६६
ारे हैं,
नड़ रहे
श चंद्र
जान
अपना
मैदान

मिताभ
गवाना
नाम हैं
ले रहे

म खुद
चुनाव
में भी
ारे हैं।
मिश्र

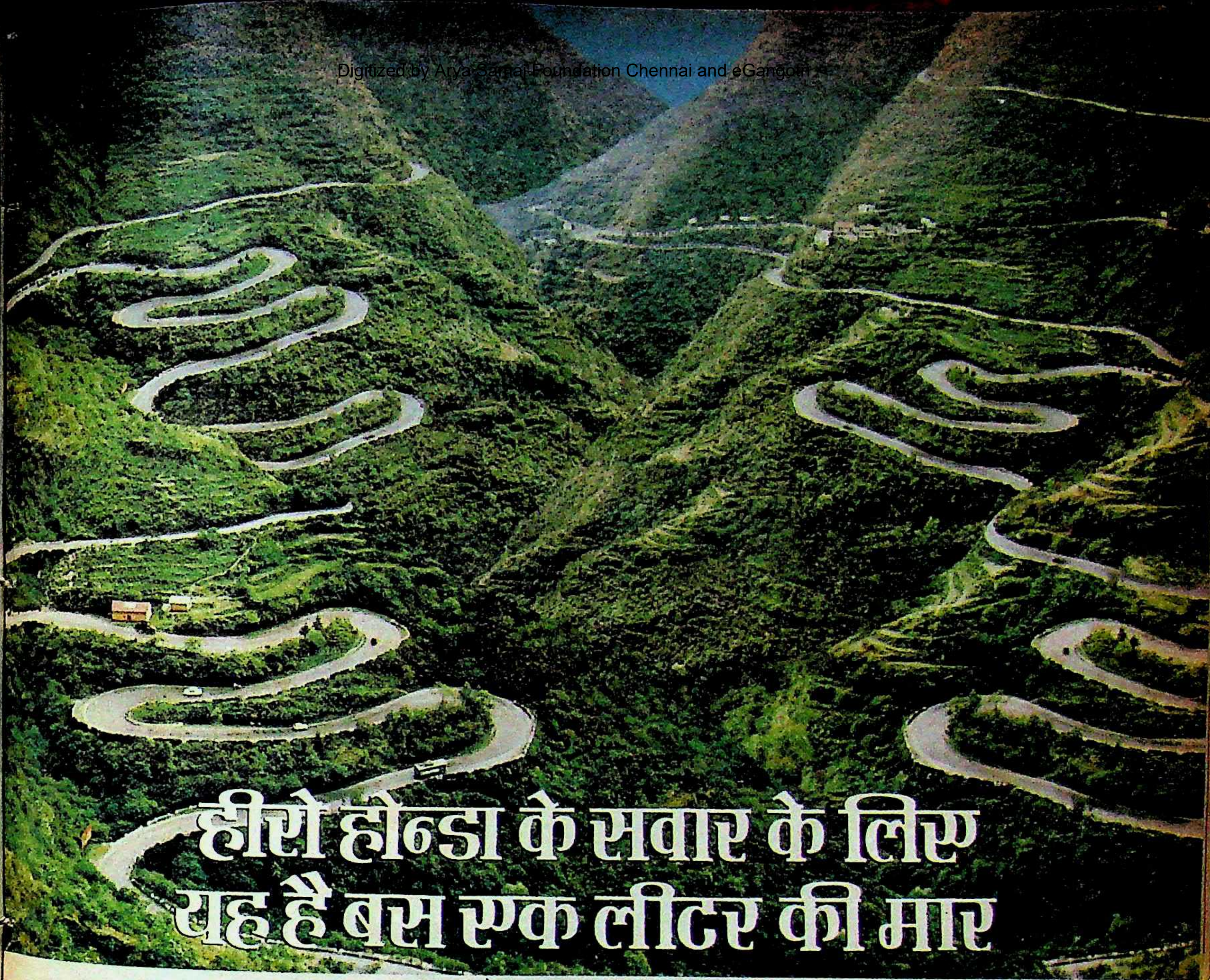

हीरो होन्डा के सवार के लिए यह है बस एक लीटर की मार

हम यह बात ज़रा भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहे। अगर आप हीरो होन्डा सी डी 100 पर सवार हैं तो एक लीटर पेट्रोल आपको बहुत दूर–80 किलोमीटर दूर तक–ले जाएगा।

एक लीटर में आपको *इतनी* दूर भला और कौन सी मोटरसाइकिल ले जाएगी?

टैंक भरिए. और चलते चलिए.

होन्डा की तकनीकी श्रेष्ठता हीरो होन्डा सी डी 100 के असाधारण 4-स्ट्रोक इंजन की हर विशेषता में देखी जा सकती है। ईंधन पूरी मात्रा में जलने के कारण देखभाल में आसानी, 80 किलोमीटर प्रति लीटर* चलने की कुशलता, और साथ में प्रदूषणहीन एग्ज़ास्ट सुनिश्चित हैं–मीलों मील बिना-परेशानी अच्छी सेवा के लिए।

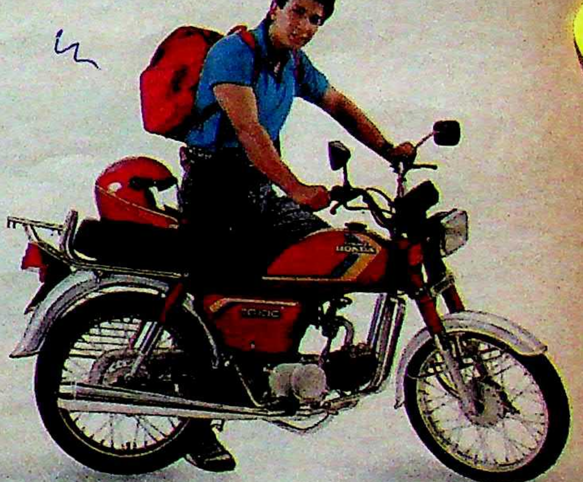

हां, हीरो होन्डा को लाखों ने अपनाया है। उन्हीं ने इसे भारत की सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिल बनाया है।

HERO HONDA

आपका शानदार हमसफ़र!

* *40 कि.मी. प्रति घंटा और 130 किलो भार सहित.*

HTA 6347H

igitiz Samaj Fo hennai and eGangotri

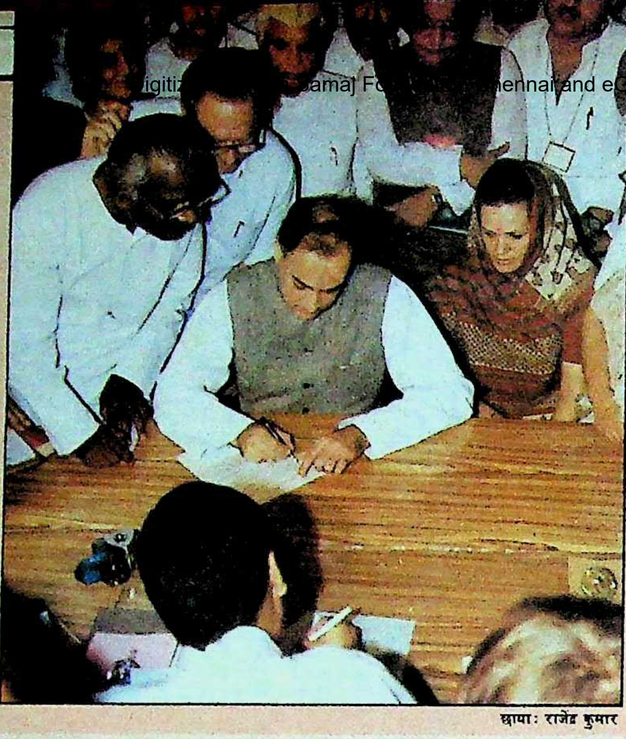

गांधी से गांधी का मुकाबला: राजीव गांधी नामांकन पत्र भरते हुए

छाया: राजेंद्र कुमार

चुनावी महाभारत: मोर्चाबंदी कैसे हो रही है?

पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने योद्धाओं को चुनाव-रणभूमि में उतार दिया है। अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस-इ के साथ विपक्ष की सीधी टक्कर होने जा रही है। विपक्ष ने कांग्रेस को पराजित करने के लिए जो मोर्चाबंदी बनायी है, क्या वह कारगर हो पायेगी? कांग्रेस किस बलबूते पर यह चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बोफोर्स दलाली के नित नये उघड़ते रहस्य और राम जन्म मंदिर के प्रस्तावित शिलान्यास से उभरते खतरों के बीच शुरू हुए चुनाव का आकलन:

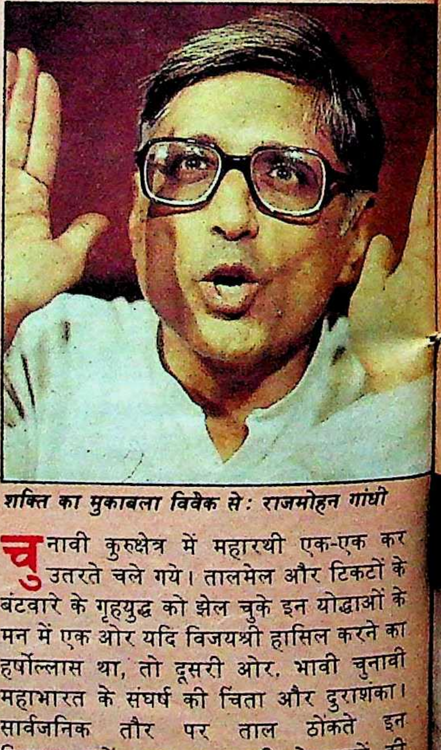

शक्ति का मुकाबला विवेक से: राजमोहन गांधी

चुनावी कुरुक्षेत्र में महारथी एक-एक कर उतरते चले गये। तालमेल और टिकटों के बंटवारे के गृहयुद्ध को झेल चुके इन योद्धाओं के मन में एक ओर यदि विजयश्री हासिल करने का हर्षोल्लास था, तो दूसरी ओर, भावी चुनावी महाभारत के संघर्ष की चिंता और दुराशंका। सार्वजनिक तौर पर ताल ठोंकते इन सिपहसालारों द्वारा कामयाबी के दावों की भरमार थी, तो अंदर-ही-अंदर जोड़-तोड़ और गोटियां फिट करने की आकांक्षा और अथक प्रयास। कारण, पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए ही १९८९ के अंत में होनेवाला आम चुनाव चार दशक पुराने भारतीय लोकतंत्र का कदाचित सर्वाधिक विकट, महंगा, और हिंसक होने की संभावना से परिपूर्ण है।

एक तरह से देखा जाये, तो चुनाव परिणाम

आखिर पहुंच ही गये: फतेहपुर में वीपी सिंह परचा दाखिल करते हुए

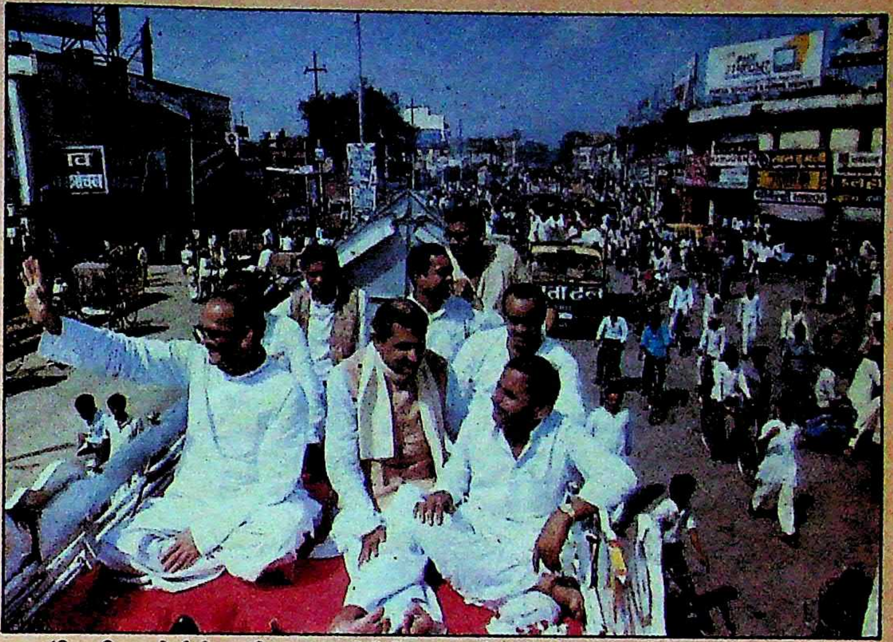

क्या मंजिल मिल सकेगी ? : क्रांति रथ पर वीपी सिंह अन्य नेताओं के साथ छाया: मनमोहन शर्मा

सबको टिकट चाहिए: प्रत्याशियों से घिरे मुलायम सिंह यादव छाया: गिरीश श्रीवास्तव

अंततः पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। यदि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के हाथ पराजय आती है, तो कांग्रेस में विभाजन अपरिहार्य होगा। इसके विपरीत यदि हार विपक्ष के खाते गयी, तो १२ वर्ष के बनवास के बाद, बमुश्किल एकजुट हुआ विपक्ष फिर से बिखर जायेगा। नतीजतन, युद्धपूर्व की तैयारी और मोर्चाबंदी में एकमात्र लक्ष्य येन-केन प्रकारेण विजय हासिल करना रहा। यही कारण है कि चुनाव घोषणा पूर्व तक दोनों पक्षों से जारी बयानबाजी में सिद्धांतों की दुहाई और नीतिगत घोषणाएं चुनावी अखाड़े में उतरते-उतरते ताक पर रख दी गयीं। इसका पहला आभास स्वयं उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया से मिला।

वायदा खिलाफी : चुनाव के ठीक पहले तक कांग्रेस और विपक्ष दोनों ही महिलाओं को तीस फीसदी सीटें, नवयुवकों को समुचित प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति-जनजाति को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने, माफिया सरगनाओं, अपराधियों और भ्रष्ट तत्वों को उम्मीदवार न बनाने की पुरजोर घोषणाएं कर रहे थे। पर चुनावी महाभारत से पहले ही दोनों पक्षों में मचे टिकट बंटवारे के महासंग्राम में ये सभी घोषणाएं धरी-की-धरी रह गयीं। वायदाखिलाफी का आलम यह रहा कि महिलाओं को समुचित, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व का ढिंढोरा पीटनेवाले जनता दल ने न सिर्फ तीस की जगह मात्र तीन फीसदी महिलाओं को टिकट दिये, बल्कि महिला जनता दल की अध्यक्ष प्रमिला दण्डवते की अगुवाई में इसका विरोध प्रकट करने गये सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अपमानित करने में भी संसदीय दल के अध्यक्ष चौ० देवीलाल ने कोई कोताही नहीं बरती। देवीलाल ने क्रुद्ध होकर कहा, "मैं जानता हूं कि महिलाओं को राजनीति में कहां तक आगे लाना है।" उन्होंने पूछा, "तुम लोगों को महिलाओं की ठेकेदारी किसने दे दी है। तुम थोड़ी सी शहर की पढ़ी-लिखी फैशनपरस्त औरतें पता नहीं क्या सोचती और करती रहती हो। हमें भारत को भारत ही रखना है अमरीका नहीं बनाना है। हमारे यहां औरतें मर्दों के कहने पर वोट देती हैं।"

कांग्रेस भी पीछे नहीं। महिलाओं को ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन देनेवाले सत्ता दल ने टिकट बांटते समय मात्र ११ प्रतिशत महिलाओं को ही टिकट दिये। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति का आलम यह रहा कि टिकट बंटने के लगभग एक हफ्ते पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जियाउर्रहमान अंसारी पर अपने कार्यालय में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बलात्कार के प्रयास के सरेआम आरोप के बावजूद उन्हें बेखटके टिकट दे दिया गया। सत्ता के दलालों और असामाजिक तत्वों, माफिया सरगनाओं के सफाये की बार-बार रट लगानेवाले राजीव गांधी को काली पांडे (गोपालगंज, बिहार), तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज, बिहार) और अब्दुर्रहमान अंतुले (कोलाबा) को टिकट देने में कोई भी परेशानी नहीं महसूस हुई।

चुनावी मोर्चाबंदी का एक अन्य दिलचस्प तथ्य यह रहा कि उम्मीदवारों और टिकट के बंटवारे को लेकर लगायी गयी तमाम अटकलें, अफवाहें और खबरें भी लगभग झूठी साबित हुईं। आकस्मिक चुनाव घोषणा के तुरंत बाद सत्ता गलियारों में यह चर्चा आम रही कि कांग्रेस की

हौसला बुलंद : एनटीआर

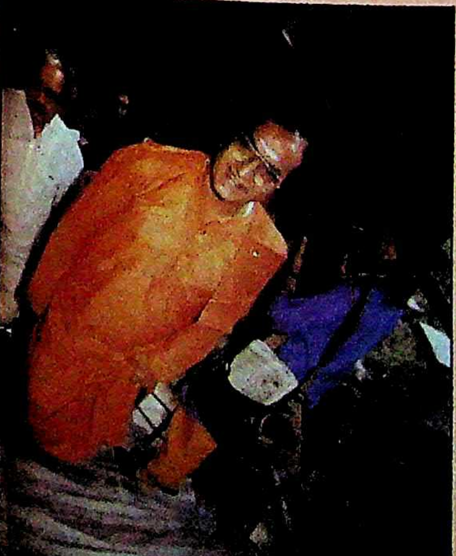

चुनावी तैयारी भरपूर है। यहां तक कि उम्मीदवारों की सूची भी लगभग तैयार है। जानकार सूत्र यह दावा करते रहे कि पिछले छह महीनों से चल रही उम्मीदवारों के चयन की विभिन्न कसरतों और कंप्यूटरी आकलनों से एक बेहद कसी-मजी सूची सामने आनेवाली है। इस दौरान यदि ३० से लेकर ६० फीसदी नये चेहरों का पुरजोर दावा दोहराया जाता रहा, तो अनेक दिग्गजों के पत्ते साफ होने की खबरें भी गरमाती रहीं। किंतु जारी की गयी सूचियां चुनाव घोषणा से कम चौंकानेवाली नहीं थीं। कारण, उनमें नये की जगह पुराने चेहरों और उन्हीं तत्वों की भरमार थी, जिनसे पीछा छुड़ाने की बात शीर्ष नेतृत्व निरंतर करता रहा है। लेकिन अब ऐसे तत्व उसे चुनाव-विजय के लिए अपरिहार्य नजर आने लगे हैं।

जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार, "प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हाल का प्रत्येक कदम बोफोर्स तोपों के धमाके से कांग्रेसी शिविर में मचे हड़कंप, निराशा और हताशा की निशानी है।" स्थिति दिनोदिन इतनी गंभीर हुई है कि आज कांग्रेस अथवा प्रधानमंत्री राई-रत्ती जोखिम नहीं उठा सकते। विपक्ष संबंधी कांग्रेसी आकलन की विफलता भी रणनीति में रातोरात परिवर्तन करने की विवशता बनी है। उल्लेखनीय है कि आकस्मिक चुनाव घोषणा के समय अनुमान लगाया गया था कि आपसी गुत्थमगुत्था में उलझा विपक्ष सीटों के बंटवारे और वाम-भाजपा से तालमेल के मुद्दे पर टूट-बिखर जायेगा। नतीजतन, न तो वह एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार ही खड़ा कर सकेगा न ही कांग्रेस को कोई बड़ी चुनौती दे पायेगा। हुआ उल्टा। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 'माया' से बातचीत में कहा, "हम तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने चुनाव घोषित कर विपक्षी एकता में सीमेंट का काम किया है। एक निश्चित समय सीमा ने विपक्ष को तमाम गिले-शिकवे भुला, चटपट फैसला लेने और एकजुट होने को उद्यत किया।"

चयन प्रक्रिया में परिवर्तन : इसी एकजुटता ने कांग्रेसी गणित को गड़बड़ा दिया। ज्यों-ज्यों विपक्ष के बीच सुलह-समझौते की खबरें फैलीं, त्यों-त्यों कांग्रेसी शिविर में चिंता गहराती गयी। इससे स्वयं प्रधानमंत्री भी अछूते न रहे। जानकार सूत्रों के अनुसार संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले से ही प्रधानमंत्री विरोधी खेमे की एक-एक खबर हासिल कर रहे थे। बैठक के दौरान उनकी बेताबी का आलम यह था कि वे खुद थोड़ी-थोड़ी देर बाद वहां के ताजातरीन समाचार मांग रहे थे। इसी के बीच हुए विचार-विमर्श का निष्कर्ष रहा कि विपक्ष के मजबूत उम्मीदवार के विरुद्ध किसी नये, कम अनुभवी उम्मीदवार को खड़ा करने का प्रयोग महंगा साबित हो सकता है। इसलिए अनुभवी मौजूदा सांसदों को ही मैदानेजंग में उतारा जाये।

खानदानी प्रचार : एक प्रचारक

छाया : एस पाल

अधिकाधिक पुराने सांसदों को पुनः टिकट देने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण किसी संभावित विद्रोह और भितरघात से बचना भी रहा। गुटबंदी के संक्रामक रोग से ग्रस्त कांग्रेस में टिकटों की ज्यादा काट-छांट से असंतुष्ट पार्टी उम्मीदवारों की बाढ़ आ जाने का भी खतरा था। मसलन, सीटों के प्रति संवेदनशीलता की स्थिति यह थी कि कांग्रेस के अंदर की 'लाबियों' की बात तो दरकिनार एक अकेले व्यक्ति तक की घुड़की के सामने शीर्ष नेतृत्व को घुटने टेकने पड़े। सूचना प्रसारण मंत्री कमलाकांत तिवारी अपनी बक्सर की सीट छोड़कर गोपालगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। जहां से पिछले चुनाव में काली पांडे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे और जो हाल में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तिवारी की मंशा की भनक पाते ही काली पांडे ने चेतावनी दी कि उस स्थिति में वे फिर पहले की तरह अपने क्षेत्र से निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर दुबारा लोकसभा में आ जायेंगे। पांडे की घुड़की रंग लायी और शीर्ष नेतृत्व ने तिवारी को अपना बक्सा बांधकर वापस बक्सर जाने का आदेश दे दिया।

सुरक्षित सीट तलाशने वाले तिवारी अकेले नहीं थे। मेरठ से दो बार सांसद रह चुकीं केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मोहसिना किदवई भी किसी सुरक्षित सीट की खोज में थीं। उन्होंने लखीमपुर खीरी की सीट चुन भी ली थी। किंतु संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान श्रीमती किदवई की इस प्रार्थना को सुनते ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी का

BOFORS बोफोर्स चश्मा प्रदर्शन

विपक्ष का मुद्दा : दिल्ली में बोफोर्स चश्मा प्रदर्शन

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

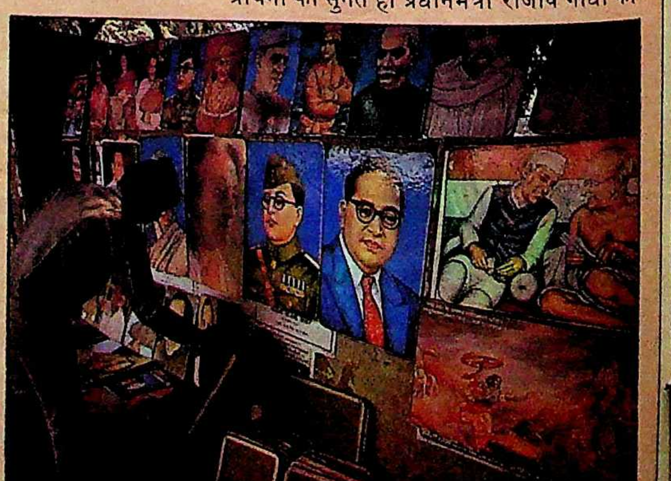

जिनकी याद चुनाव के समय आती है : कैलेंडरों की बिक्री

छाया : एस पाल

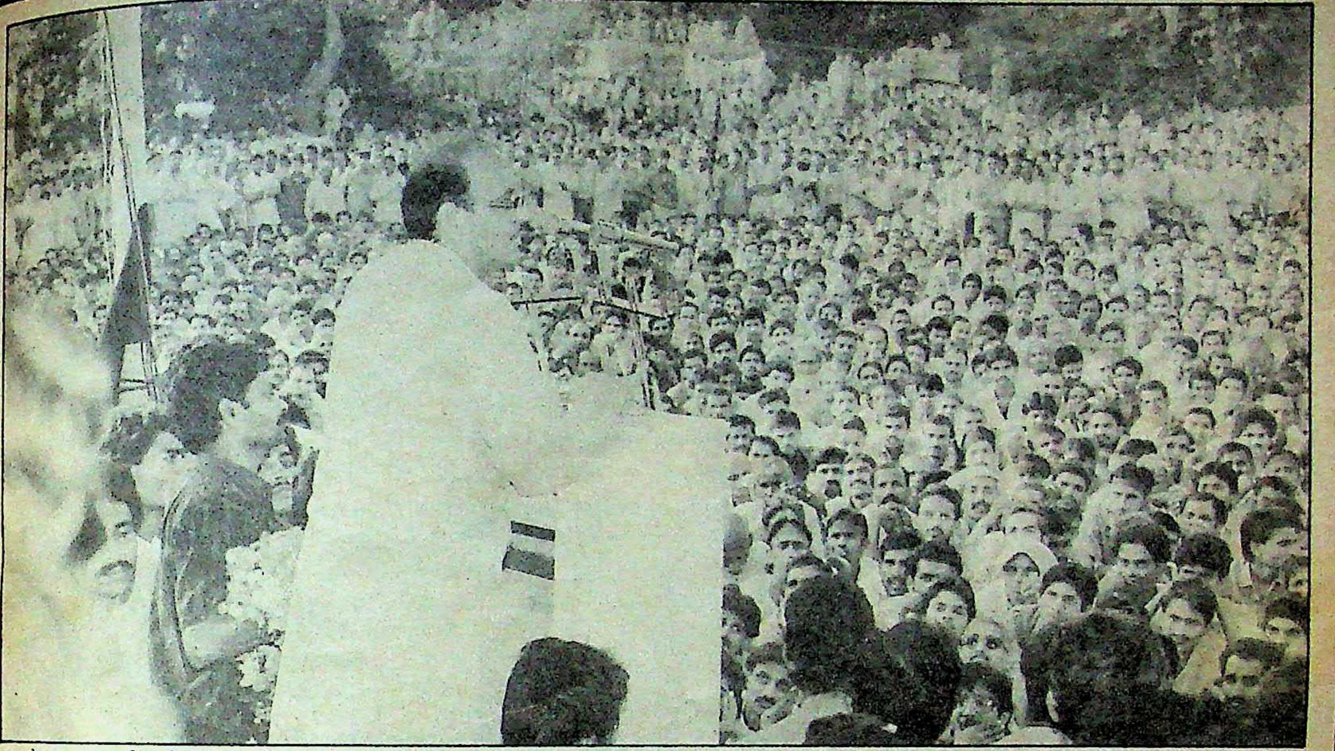

अब फैसला आप करें : वीपी सिंह फतेहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए

छाया: मनमोहन शर्मा

चेहरा तमतमा उठा। वे बोले, "मैं किस-किस को सुरक्षित सीट दूगा। यदि दो बार सांसद रह चुके लोग भी अपनी सीट सुरक्षित न बना पाये, तो हो चुका।" हारकर श्रीमती किदवई को दुखी मन से मेरठ की अपनी पुरानी डगर पर रवाना होना पड़ा।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया में आये परिवर्तन के पीछे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह दीगर बात है कि दो दिन पहले ही सभी मुख्यमंत्रियों और प्रदेशाध्यक्षों से एक पंक्ति की इस घोषणा पर दस्तखत ले लिये गये थे कि प्रधानमंत्री का चयन सर्वमान्य होगा, किंतु विपक्ष के बढ़ते हौसलों और कांग्रेसियों में बढ़ती पस्तहिम्मती ने पासा कुछ ऐसा पलटा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की सलाह लेने-मानने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का ठसका तो यह रहा कि जब उत्तर प्रदेश के लोकसभा टिकटों का मशविरा चला, तो उसमें शामिल नहीं हुए। पर तुर्रा यह रहा कि जिन्हें चाहते थे, उन्हें सीटें मिल गयीं और नैनीताल की सीट पर आंख लगाये प्रधानमंत्री के खासुलखास बने रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत ने किसी अन्य जगह से खड़े होने से इनकार कर दिया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्रियों की सलाह रही कि नये चेहरों को लाने की जगह मौजूदा सांसदों को अधिकाधिक टिकट देना लाभदायक रहेगा।

सांसदों से भय : कदाचित, पुराने सांसदों को टिकट देने के पीछे संवैधानिक मजबूरी भी

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

जाखड़ का जिक्र कहां है ? : देवीलाल

रही। चूंकि लोकसभा भंग नहीं हुई है, इसलिए मौजूदा सांसदों को यह अधिकार है कि किसी गंभीर संकट के उपस्थित होने पर वे संसदीय दल की बैठक कर न सिर्फ प्रधानमंत्री बदलने की मांग ही पेश कर सकते हैं, बल्कि उसे पारित भी करा सकते हैं। बोफोर्स के कुछ अन्य दस्तावेजों के छपने और उनसे शीर्ष नेतृत्व के जुड़ने का दावा 'हिन्दू' के संयुक्त संपादक एन राम ने हाल में विदेश से भी पेश किया है। ऐसी सूरत में मौजूदा सांसदों को टिकट न मिलने का असंतोष दस्तावेजों को नैतिक आधार बना उन्हें बगावत पर आमादा कर सकता था। अतः पहले से ही पार्टी में मौजूद असंतोष और भितरघात के माहौल में भारी तादाद में टिकट काटने का कदम आत्मघाती सिद्ध होता।

उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में ही कांग्रेस को परिवर्तन नहीं करना पड़ा, बल्कि लोकसभा-विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का इरादा भी बदला गया। विश्वसनीय सूत्रों ने 'माया' को बताया कि चुनाव तिथि पर निर्णय के लिए १६-१७ अक्तूबर को जब विचार-विमर्श हुआ, तो लोकसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार सहित नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की बात हुई थी। इसका मूल कारण नारायण दत्त तिवारी द्वारा दी गयी एक आठ सूत्री रणनीति थी, जिसमें विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लाभों का ब्यौरा था। मुख्य सूत्र ये थे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में दब जायेगा। दूसरे, लोकसभा सीटों के बंटवारे को तो विपक्ष भले ही सरंजाम दे दे, किंतु अल्प समय, कम तैयारी और आपसी रस्साकशी के चलते विधानसभा सीटों के बंटवारे के प्रश्न पर उसमें खुलकर सरफुटौवल होगी। कांग्रेस संसदीय दल के महामंत्री पीएन सुकुल का 'माया' से कहना था, "लोकसभा व विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराना कांग्रेस की वह मोर्चाबंदी होगी जो राष्ट्रीय मोर्चे को तोड़ेगी।" प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तिवारी के आठ सूत्री प्रस्ताव को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सहमति प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने इसके लिए आरके

धवन को आवश्यक कदम उठाने की हिदायत दी थी और धवन ने चुनाव आयुक्त पेरी शास्त्री से संपर्क साधकर उन्हें राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए आगाह कर दिया था। इसी दौरान यह खबर दावानल की भांति राजधानी में फैल गयी थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश आदि में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राजधानी में मौजूदगी ने इस खबर को और अर्थपूर्ण बना दिया था।

किंतु जिस प्रकार लोकसभा के लिए नये उम्मीदवारों का चयन कार्यक्रम अंतिम क्षणों में रद्द हो गया, उसी प्रकार लोकसभा के साथ अधिकांश राज्यों के विधान सभा चुनाव कराने का प्रयास भी धरा-का-धरा रह गया। जानकार सूत्रों के अनुसार, इस कदम का पार्टी सांसदों-विधायकों ने जबर्दस्त विरोध किया। दलील रही कि एक साथ चुनाव कराने से बोफोर्स का मामला भले ही दब जाये, किंतु जो स्थानीय मुद्दे उभरेंगे, उनसे विपक्ष को लाभ होगा। जो रस्साकशी विपक्ष के बीच मौजूद थी, वह शासक दल में प्रारंभ हो गयी। जनता दल के वरिष्ठ नेता इंद्र कुमार गुजराल के अनुसार, "कांग्रेस ने इस भय से अनेक राज्यों, मसलन बिहार, मप्र, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं कराये, क्योंकि उसे अंदेशा था कि वहां पार्टी में जारी भारी गुटबंदी और आपसी उठापटक महंगी पड़ेगी।"

यह जगजाहिर है कि बिहार में मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तारिक अनवर और केंद्रीय श्रममंत्री बिंदेश्वरी दुबे के विभिन्न गुट एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगातार लगे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधव राव सिंधिया अपने-अपने खेमे में ताल ठोक रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी, केंद्रीय योजना मंत्री माधव सिंह सोलंकी के गुटों के बीच घमासान मची हुई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री अंतुले एक दूसरे का पत्ता साफ करने में रात-दिन एक किये हुए हैं, तो राजस्थान में मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा अशोक गहलौत की टांग खींचने में लगे हैं।

अधिकांश राज्यों में चुनाव न कराने के फैसले को बदलने के पीछे की समझदारी का एक कारण यह भी रहा कि एक बार में सब कुछ दांव पर लगाना उचित नहीं होता। लोकसभा चुनावों में खुदा-न-खास्ता पराजय की स्थिति में कुछ मजबूत गढ़ (राज्य) अवश्य सुरक्षित रखने चाहिए, जिससे वहां से आगामी महाभारत की चांदमारी का अभ्यास किया जा सके। इसके अलावा हार के बाद पार्टी में संभावित भगदड़ को भी इसकी मदद से रोका जा सकता है।

ज्यादा-से-ज्यादा नये उम्मीदवारों को लाने और अधिकांश राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के चौंकानेवाले दोनों ही फैसलों को वापस लेने के बावजूद कांग्रेसी शिविर में टिकटों के बंटवारे का रास्ता तमाम अड़चनों और भवबाधाओं से परिपूर्ण रहा। वैसे तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीन-तीन सूचियां पहले से ही तैयार करवायी हुई थीं। एक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची। दो, राज्यों के प्रभारी केंद्रीय महासचिवों द्वारा समन्वय समिति और केन्द्रीय पर्यवेक्षकों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की गयी सूची। तीन, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष द्वारा बनायी गयी सूची। इनके अलावा, दिल्ली ने केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों के मार्फत भी राज्यवार संभावित उम्मीदवारों के नामों और उनकी स्थितियों के बाबत एक सूची तैयार की हुई थी।

माहौल : टिकट बंटवारे की इतनी विस्तृत और 'वैज्ञानिक' प्रक्रिया अपनाने के बावजूद अंतिम समय में मचनेवाली अफरातफरी और घात-प्रतिघात को रोका नहीं जा सका। चुनाव घोषणा के अगले दिन ही जहां राजधानी में टिकटार्थियों का महाकुंभ लग गया, वहीं प्रमुख कांग्रेसी-नेताओं के यहां कपड़े-फाड़ने और मारपीट होने की तमाम दफे नौबतें आयीं। राज्यों के भवनों, पांच तारा होटलों से लेकर पुरानी दिल्ली, पहाड़गंज के गंदे होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं तक राजधानी का शायद ही कोई ऐसा कोना हो, जहां देश के दूरदराज तक से आये खद्दरधारी टिकटार्थी मौजूद न हों।

उधर, दिल्ली दरबार के खास सिपहसालार अपनी-अपनी लाबी के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा टिकट दिलवाने और प्रतिद्वंद्वी खेमों के टिकट कटवाने की जोड़तोड़ में भागमभाग मचाये थे। टिकट दिलवाने में प्रधानमंत्री के किस सलाहकार की ज्यादा चल रही है, किसके पर कतर गये हैं—की परस्पर विरोधी अफवाहों, खबरों से राजधानी पटी पड़ी थी। चुनाव घोषणा

आठवीं लोकसभा

दलीय स्थिति

पार्टी	दिसंबर १९८४	७-४-१९८९	१५-१०-१९८९
कांग्रेस-इ	४०५	३९७	३८३
तेलुगुदेशम	३०	२८	—
सीपीएम	२२	२२	—
सीपीआई	६	६	—
भाजपा	२	२	—
द्रमुक	२	२	—
जनता पार्टी	१०	१०	२ (जद)
लोकदल	३	३	१
कांग्रेस-स	४	४	—
आ०इ० अन्नाद्रमुक	१२	१०	१०
असम गण परिषद	—	६	१
नेशनल कांफ्रेंस	३	३	२
मुस्लिम लीग	—	२	२
कांग्रेस-जे	२	१	१
केरल कांग्रेस	२	२	२
फारवर्ड ब्लाक	२	२	—
आरएसपी	३	३	—
अकाली दल (बादल)	—	३	—
अकाली दल (बरनाला)	—	२	—
निर्दलीय	५	६	४
असंबद्ध	—	१०	३
नामांकित	—	२	२
अन्य	५	३	५
रिक्त स्थान	२७	१६	१२९
योग	५४५	५४५	५४५

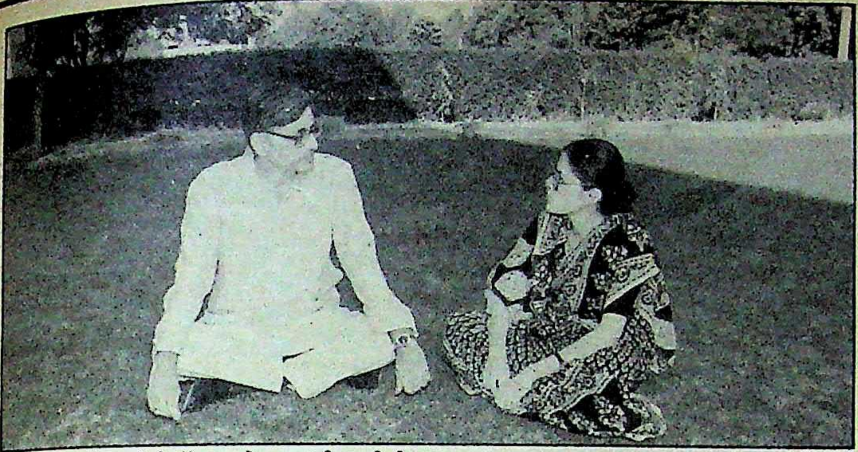

मैदान में गांधी: अमेठी में राजमोहन गांधी पत्नी के साथ

छाया: मनमोहन शर्मा

टोपी की लाज की चिंता: निर्णायक मोर्चे के सेनापति नारायण दत्त तिवारी

छाया: मनमोहन शर्मा

के फैसले के दिन सुबह प्रधानमंत्री निवास पर हुई बैठक में महामंत्री गुलाम नबी आजाद की गैरमौजूदगी ने एक अफवाह को जोर दिया—आजाद का पत्ता साफ। फिर खबर आयी कि वे एक सौ चार डिग्री बुखार के चलते बैठकों में नहीं जा पा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब से आये टिकटार्थी इस बीमारी की असलियत और राजनीतिक मतलब पर अटकलें लगाकर दूसरे दरवाजे ढूंढ़ ही रहे थे कि तीन दिन की गहरी बीमारी के बाद गुलाम नबी आजाद घर के बाहर निकले। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में न केवल १, राजाजी मार्ग स्थित आजाद का बंगला टिकटार्थियों की भीड़ से खचाखच भर गया, बल्कि बाहर दूर सड़क तक फैले टिकटार्थियों ने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। बीमारी से कमजोर और थके आजाद को उनके सहयोगी बमुश्किल भीड़ से छुड़ाकर पीछे के दरवाजे से निकालकर संसदीय बोर्ड की बैठक में भेज पाये।

राजधानी में देशभर से जुटे टिकटार्थियों के इस रेले में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आये लोगों का था। वजह, जहां लोकसभा में सबसे ज्यादा ८५ सीटें केवल उत्तर प्रदेश की ही हैं, वहीं इस प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव होने से विधानसभा प्रत्याशियों का भी पूरा जमावड़ा लखनऊ से उठकर दिल्ली चला आया था। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय महामंत्री गुलाम नबी आजाद के घर पर टिकट बंटवारे के दौरान सबसे बड़ा मेला लगा रहा। प्रधानमंत्री की विश्वस्त सलाहकार और केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित, उप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद बलराम सिंह यादव के घर पर भी किसी भी केंद्रीय मंत्री के निवास से ज्यादा भीड़ थी। उप्र से आये अधिकतर टिकटार्थी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को खोजते ही रह गये। आश्चर्यजनक रूप से रायसीना रोड के कोने पर अकसर भीड़ से भरी रहनेवाली तिवारी की कोठी में सन्नाटा छाया रहा। टिकटार्थियों के जत्थे दिन भर फाटक तक आकर वापस लौटते रहे। तिवारी अपने इस 'अज्ञातवास' के दौरान ओखला स्थित गेस्ट हाउस में ही टिके रहकर दूर से अपनी गोटियां चलते रहे।

अन्य प्रदेश भवनों और केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं के घरों का दृश्य इससे कुछ अलग नहीं था। बिहार की भीड़ बिहार भवन के अलावा मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, तारिक अनवर और सूचना प्रसारण राज्यमंत्री कमलाकांत तिवारी के बंगलों में जुटी थी। मप्र भवन और मुख्यमंत्री वोरा के राजधानी निवास, माधव राव सिंधिया और अर्जुन सिंह के बंगलों का राज्य के टिकटार्थी लगातार चक्कर काट रहे थे। राजस्थान भवन में जितनी भीड़ थी, लगभग उतनी ही भीड़ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजेश पायलट की कोठी पर थी, जहां एक बड़ा तंबू लगा हुआ था, ५०० कुर्सियां सजी हुई थीं और हलवाई कई दिनों तक पूड़ियां तलता रहा था।

टिकट कैसे बंटे: अफरातफरी के इस आलम के बीच जारी की गयी किस्तवार सूचियों ने टिकटार्थियों की भीड़ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्रथम दो सूचियों के ३२७ घोषित उम्मीदवारों में नये चेहरे मात्र ४६ रहे। ऐसा भी नहीं कि सभी ४६ नये चेहरों को पुरानों का टिकट काटकर शामिल किया गया हो। दरअसल, इनमें अधिकांश सीटें वे थीं जो दलबदल अथवा निधन के कारण रिक्त पड़ी थीं। मुश्किल से दो दर्जन मामले ऐसे थे, जहां मौजूदा सांसदों को नकारा गया। महाराष्ट्र के गुरुदास कामथ के बारे में औपचारिक रूप से तो यह कहा गया था कि बंबई की जिस सीट का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां से उनका पुनः जीतना संदिग्ध था। किंतु जानकार सूत्रों के अनुसार कारण कदाचित उनका कुछ समय पूर्व का वह विद्रोही तेवर था, जिसके चलते उन्होंने सैद्धांतिक मुद्दे उठाते हुए अग्रिम संगठनों के प्रभारी महासचिव आस्कर फर्नांडीस पर बेजा हस्तक्षेप का आरोप लगा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन उन्हें भी टिकट मिल गया। इसी प्रकार अन्य नेता भी या तो सलाहकारों की नापसंदगी और लाबिंग का शिकार रहे अथवा अंतिम क्षणों में उन्हें काबिल मान लिया गया। जब इसकी चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय के एक उच्चाधिकारी से चली, तो उन्होंने इससे सरासर इनकार किया। उनके अनुसार टिकट बांटने का सबसे सीधा मापदंड पिछले चुनाव में मिली विजय और मत रहे। श्रीमती गांधी की शहादत की आंधी में जीतकर आये जिन सांसदों की जीत २५,००० मतों से कम की थी, उनका पत्ता पहले ही साफ कर दिया गया। २५ से ५० हजार तक मतों से जीते लोगों के बारे में गहन विचार-विमर्श हुआ और ५० हजार से अधिक मतों से विजयी लोगों का टिकट पक्का माना गया। कदाचित इसी गणित के चलते उन

श्रीपति मिश्र को टिकट मिला, जिनके लिए चुनाव अभियान जोर-शोर से चलाना दरकिनार दस कदम पैदल चलना दूभर रहेगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की विशिष्ट अनुकंपा के कारण उन पुष्पादेवी सिंह को टिकट दिया गया है जो पैर में चढ़े प्लास्टर के कारण अस्पताल में पड़ी हैं। इसी के तहत उन मुखर कांग्रेसियों को भी टिकट देना पड़ा है जिन्होंने कांग्रेस-इ सरकार की खुलकर आलोचना की थी। जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, सीपीएन सिंह और शांति धारीवाल। इसी मापदंड के चलते कांग्रेस को विश्वनाथ प्रताप सिंह के सगे समधी आनंद सिंह को भी तमाम खबरों-संदेहों के बावजूद टिकट देना पड़ा।

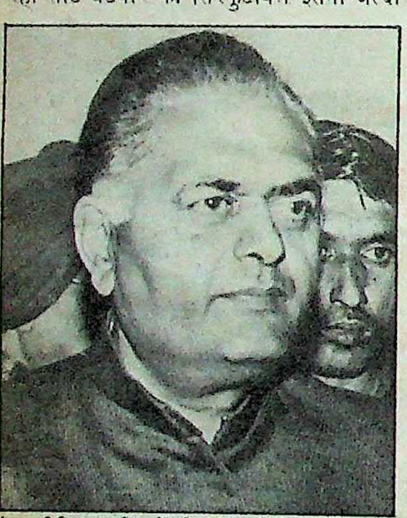
'राजनीतिक जमींदारों' के मारे: केसी पंत

विपक्ष की हलचल: उम्मीद के विपरीत चौंकानेवाला काम विपक्ष ने भी किया। न सिर्फ कांग्रेसी खेमे, बल्कि खुद विपक्षी नेताओं तक को शायद यह अंदाज नहीं था कि महीनों से चली आ रही सीट बंटवारे की सिरफुटौवल इतनी जल्दी और आसानी से सुलट जायेगी। विशेषकर, तब जब राष्ट्रीय मोर्चा १८ अक्तूबर को अपने अध्यक्षमंडल की बैठक बुलाने के असफल प्रयास के झटके से गुजर चुका था। ज्ञात रहे कि पूरी कोशिश के बावजूद यह बैठक इसलिए नहीं हो पायी थी, क्योंकि द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने अपनी 'व्यस्तता' का कारण बताते हुए आने में असमर्थता जतायी थी। राष्ट्रीय मोर्चा में इस बात को ले चिंता इसलिए और अधिक बढ़ी कि कांग्रेस गत कुछ महीनों से करुणानिधि को मनाने, पटाने और धमकाने के हथकंडों को लगातार अपनाती रही थी। पर्यवेक्षकों में यह धारणा बनी कि १३ वर्ष के बनवास के बाद सत्तासुख भोग रहे करुणानिधि महज विपक्षी एकजुटता के चलते अपनी कुर्सी खतरे में नहीं डालेंगे। समस्त आशंकाएं तब निराधार सिद्ध हुईं, जब २० तारीख की बैठक में न सिर्फ करुणानिधि ने शिरकत ही की, बल्कि आनेवाले दिनों में मोर्चे के अन्य घटकों के साथ सीटों का निर्विघ्न बंटवारा भी कर लिया।

विधानसभा चुनाव, १९८५

(दलीय स्थिति)

प्रदेश का नाम	सीटों की संख्या	कांग्रेस-इ	अन्य प्रमुख दल	अन्य
आंध्र प्रदेश	२९४	४९	तेलुगुदेशम २०२	४३
उड़ीसा	१४७	११७	जनता पार्टी २०	१०
राजस्थान	२००	११३	भाजपा ३८	४९
हिमाचल प्रदेश	६८	५५	भाजपा ७	१६
महाराष्ट्र	२८८	१६२	कांग्रेस (स) ५४	७२
बिहार	३२४	१९२	दमकिपा ३८	९४
गुजरात	१८२	१४९	जनता पार्टी १४	१९
उत्तर प्रदेश	४२५	२६६	दमकिपा ८५	७४
कर्नाटक	२२४	६६	जनता पार्टी १३९	१९
मध्य प्रदेश	३२०	२५०	भाजपा ५८	१२
सिक्किम	३२	१	एसएसपी ३०	१
पांडिचेरी	३०	१५	अभाअद्र ७	८
पंजाब	११७	३२	अकाली दल ७३	१२
आसाम	१२५	२५	गणपरिषद ६४	३६
पश्चिम बंगाल	२९४	४०	सीपीएम १८७	६७
जम्मू-कश्मीर	७८	२७	नेशनल कां० ४०	११
केरल	१४१	३३	एलडीएफ ७९	२९
हरियाणा	९०	५	लोकदल ५९	२६
नागालैंड	६०	३४	एनएनडीपी १८	८
मेघालय	६०	२२	एचपीयू १९	१९
त्रिपुरा	६०	२४	सीपीएम २६	१०

"तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सीटों का बंटवारा निर्विघ्न ही होना था," ऐसा मोर्चे के एक नेता ने 'माया' से हंसते हुए कहा। उनका कहना था, "हमारे मोर्चे के इन दो दक्षिणी प्रांतों में दो राजीव गांधी हैं (एनटी रामाराव, एम करुणानिधि) जिनका निर्णय सबको हर हाल मानना ही पड़ेगा।" हंसी की बात अलग, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों नेता—एनटी रामाराव और एम करुणानिधि—न सिर्फ अपनी पार्टी के एकछत्र सिपहसालार हैं, बल्कि अपने राज्यों के भी। ऐसी सूरत में निर्णय लेना और अमल कराना दोनों ही आसान होता है। हुआ भी यही। सीटों के मसले पर कुछ छिटपुट चीं-चपड़ के अतिरिक्त दोनों ही प्रदेशों में सब कुछ आशानुसार राजी-खुशी निपट गया। लेकिन हिन्दीभाषी क्षेत्रों में रस्साकशी एक ओर तो सबसे बड़े घटक जनता दल के विभिन्न धड़ों में थी, तो दूसरी ओर, विपरीत ध्रुवों पर बैठी भाजपा और वाममोर्चा के मध्य, जिनसे तालमेल कर एक के विरुद्ध—एक उम्मीदवार खड़ा करना विपक्षी जीत की पहली शर्त रही है।

जनता दल में होनेवाले घमासान का सबसे पहला संकेत चुनाव तिथि के ऐलानवाले दिन ही तब मिला, जब पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष चौ० देवीलाल ने बिना पार्टी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह से विचार-विमर्श किये हरियाणा में आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिये। अगले दिन ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल के इस कदम की कटु आलोचना करते हुए यह बयान जारी किया कि अध्यक्ष की सहमति और हस्ताक्षर के बिना कोई औपचारिक सूची जारी नहीं हो सकती। मामला हाथ से निकलता देख देवीलाल गुट ने इसी में खैर समझी की पार्टी अध्यक्ष से सुलह-समझौता कर दूसरी सूची जारी करवायी जाये। यह दीगर बात है कि जारी होनेवाली सूची में वही सब नाम थे, जिन्हें देवीलाल चंडीगढ़ में घोषित कर चुके थे।

पार्टी अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के मध्य आम सहमति से काम करने के फैसले का देवीलाल गुट ने तब भरपूर लाभ उठाया, जब उन्होंने सूचियां-विज्ञप्तियां जारी करने के पारम्परिक अधिकार से पुराने प्रतिद्वंद्वी पार्टी के प्रधान सचिव अजीत सिंह को वंचित कर दिया और अधिकार मात्र पार्टी और बोर्ड के अध्यक्षों के सुपुर्द रहा। जब प्रधान सचिव को होश आया, तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। बोर्ड की बैठक में विवाद उठाने का उनका प्रयास फौरी एकजुटता और समय की नजाकत की दुहाई पर विफल कर दिया गया।

शुरुआती कार्रवाई में ही इस प्रारंभिक झटके के बावजूद टिकट के बंटवारे में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। जैसाकि जनता दल नेताओं का दावा रहा, टिकटों का बंटवारा सर्वसम्मत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटा। जनता दल महासचिव् यशवंत सिन्हा ने 'माया' को बताया, "जिस सहूलियत से हमने यह सब निपटाया है, उसने कांग्रेस की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। सच तो यह है कि हमने सत्तारूढ़ दल के मुकाबले कहीं ज्यादा सरलता, सहजता से सभी काम निपटाये।" हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला का कहना था, "यह जानते-समझते हुए कि हम यदि न भी लड़ेंगे, तो हमारे कुछ 'मेहरबान' पत्रकार हमें अवश्य ही लड़वा देंगे। हमने निश्चय किया कि जब तक समस्त कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, हममें से कोई किसी पत्रकार से संपर्क नहीं रखेगा।" बात चौटाला ने भले ही मजाक में क्यों न कही हो, किंतु विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि स्वयं पार्टी अध्यक्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे।

व्यक्तिगत पसंद : इन तमाम सतर्कताओं के बावजूद आपसी संघर्ष को रोका नहीं जा सका। बीस फीसदी से ज्यादा सीटें ऐसी रहीं, जिन पर विपक्षी नेताओं के बीच सीधे तकरार की नौबत आ गयी। उप्र में जनता दल में पहली गंभीर कहासुनी फर्रुखाबाद की सीट को लेकर हुई। वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने प्रिय प्रत्याशी और 'चौथी दुनिया' के युवा संपादक संतोष भारतीय को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देना पड़ा। पहले दिन जारी की गयी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की टाइप सूची में संतोष भारतीय का टाइपशुदा नाम अंतिम क्षणों में पेन से कटा हुआ था।

इस सीट पर जनता दल के दूसरे प्रबल दावेदार थे, कभी चंद्रशेखर के बेहद वफादार रहने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के शिविर में आये युवा समाजवादी नेता सुधींद्र भदौरिया। संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान सुधींद्र भदौरिया की जगह संतोष भारतीय को टिकट देने के विश्वनाथ प्रताप सिंह के हठ का अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां आदि ने जबर्दस्त विरोध किया। किंतु पहले दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह संतोष भारतीय का नाम यह कहकर सूची में डलवाये रहने में सफल हो गये, "फिलहाल यह नाम यहीं छोड़कर हम अन्य नामों को निपटा लेते हैं। इसे बाद में देख लेंगे।" किंतु बैठक समाप्त होने के समय टाइप होकर सामने आयी सूची में संतोष भारतीय का नाम देखकर ये लोग (नेहरू और खां) पुनः भड़क उठे। पत्रकारों को सूची बांटने से पहले अफरातफरी में इस नाम को कलम से काटकर सूची जारी कर दी। अगले दिन जब दूसरी सूची जारी हुई, तो संतोष भारतीय का नाम उसमें फिर शामिल था। दिलचस्प तथ्य यह है कि फर्रुखाबाद की जिस सीट पर सारी लड़ाई हुई, वहां दरअसल जनता दल की अपेक्षा भाजपा की स्थिति अधिक मजबूत है। तालमेल के तहत यह सीट भाजपा को जानी थी। व्यक्तिगत पसंद से सीट देने की यह कोई अकेली घटना नहीं। घोसी की भाकपा की पारंपरिक सीट राजकुमार राय के पक्ष में छोड़ने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खुद व्यक्तिगत रूप से भाकपा के केन्द्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया था।

गुटबाजी : उप्र की अनेक सीटों पर अपने-अपने लोगों को फिट करने की होड़ में चंद सीटों पर देवीलाल और अजीत सिंह धड़े में टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। मसलन, अमरोहा में अजीत गुट कांशीराम को टिकट दिलाने पर आमादा था, तो देवीलाल गुट चंद्रपाल सिंह को टिकट दिलाना चाहता था। चंद्रपाल सिंह १९७७ व १९८० दोनों में सांसद रह चुके हैं। किंतु १९८४ में उनका तीसरा स्थान हो गया था। अजीत सिंह की दलील थी कि जिसका दूसरा स्थान हो, उसे टिकट दिया जाये। उनकी यहां नहीं चली। पर अजीत सिंह बुलंदशहर में अपने समर्थक सरवर हुसैन को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। अन्य दो सीटों पर भी खासी रस्साकशी हुई। एक, मुफ्फरनगर की कैराना सीट, दूसरी आगरा-फिरोजाबाद के निकट की जलेसर सीट। पहली सीट पर देवीलाल गुट ने वीरेंद्र वर्मा के लिए जोर लगाया, तो अजीत सिंह ने जस्टिस महाबीर के लिए। जलेसर में देवीलाल गुट मुलतान सिंह यादव के लिए जोर लगा रहा था, तो अजीत गुट सुशीला ब्रजराज सिंह के लिए। इसमें बात इस हद तक बढ़ी कि अजीत सिंह बैठक से बाहर चले गये और पार्टी अध्यक्ष को उन्हें समझा-बुझाकर वापस लाना पड़ा।

छाया : सुनील सक्सेना

यह धर्म युद्ध है : एनटीआर

गुटबंदी में मात्र यही दोनों गुट संलग्न नहीं थे। चंद्रशेखर गुट भी अपनी कार्रवाइयों में लगा था। यह दीगर बात है कि अपनी गोलियां खुद दागने की जगह इस गुट ने अपनी बंदूक अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां, चौटाला और मुलायम सिंह यादव के कंधों पर रखी हुई थीं।

स्वयं चंद्रशेखर की बलिया की सीट पहले ही दिन घोषित हो गयी थी। इसके बाद जब यकायक महाराजगंज की सीट से भी उनका नाम घोषित

लोकसभा
आमचुनावों में दलों की स्थिति
(१९६७ से १९८४)

	१९६७	१९७१	१९७७	१९८०	१९८४
लोकसभा की कुल सीटें	५२०	५१८	५४२	५४२	५४२
जिन पर चुनाव लड़ा गया	५१५	५१७	५४०	५२९	५४१
कांग्रेस-इ	२८३	३५२	१५४	३५३	४१५
संगठन कांग्रेस/कांग्रेस अर्स	—	१६	३	१३	५
भालोद/जपा	—	—	२९५	३१	१०
जनसंघ/भाजपा	३५	२२	—	—	२
सीपीआई	२३	२३	७	११	६
सीपीआईएम	१९	२५	२२	३६	२२
लोकदल/जपा (सेकुलर)	—	—	—	४१	३
तेलुगुदेशम	—	—	—	—	३०
स्वतंत्र पार्टी	४४	८	—	—	—
प्रसोपा	२३	३	—	—	—
संसोपा	२३	३	—	—	—
अन्य	४५	५३	५२	३५	४४
निर्दलीय	२०	१२	७	९	४

हुआ, तो सवालिया निशान लगना लाजिमी था। 'माया' को इसकी बाबत मिली जानकारी के अनुसार, यह सीट उन रामबहादुर सिंह को जानी थी जो सीएजी की रिपोर्ट पर इस्तीफा देनेवाले विपक्ष के १०४ सांसदों में से एक हैं। महराजगंज सिंह की पारंपरिक विधानसभा सीट रही है, पर पिछले चुनाव में वे छपरा संसदीय सीट से लड़कर चुनाव जीते थे। इस बार उन्होंने छपरा सीट स्वेच्छा से यह कहकर छोड़ दी कि वे महाराजगंज से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर इस बीच ठाकुरों के इस गढ़ में खुद चंद्रशेखर के यकायक कूद पड़ने से सिंह अधर में लटक गये।

चंद्रशेखर का बलिया और महाराजगंज, दो-दो जगहों से प्रत्याशी घोषित किया जाना खासी चर्चा का विषय रहा। आलोचकों ने इसे सीधे-सीधे उनकी पस्तहिम्मती का द्योतक माना, किंतु आज तक 'अध्यक्षजी' के नाम से पुकारे जानेवाले चंद्रशेखर की कूटनीति से परिचित राजनीतिज्ञों का मानना है कि ऐसा कर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट पुख्ता की है, बल्कि अपने गुट की झोली में एक और सीट डाल ली है। दूसरे, ऐसा कर उन्होंने एक हेगड़े-समर्थक सांसद रामबहादुर सिंह को अधर में डालकर प्रतिद्वंद्वी गुट का एक मोहरा और हिला दिया है। जनता दल के एक वरिष्ठ नेता का 'माया' से अनौपचारिक बातचीत में कहना था कि इस समय विपक्ष के लिए हर एक सीट तो महत्वपूर्ण है ही, जीतने की स्थिति में प्रधानमंत्री के चयन के दौरान उसका वजन दुगुना हो जायेगा।

उपर्युक्त छुटपुट घटनाओं के अतिरिक्त सीटों के बंटवारे में गुटबंदी हावी नहीं हो पायी, ऐसा जनता दल नेता सुरेंद्र मोहन कहते हैं। उनके अनुसार चयन में उम्मीदवार के किसी पूर्व चुनाव में प्रदर्शित जनाधार को प्रमुख मापदंड बनाया गया। इसीलिए तीन चौथाई से अधिक उम्मीदवार पूर्व सांसद अथवा विधायक हैं। दूसरे इस बात का ध्यान रखा गया कि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। किंतु पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिक ध्यान रखा गया है।

जातीय समीकरण: सुरेंद्र मोहन भले ही कुछ कहें, किंतु जनता दल द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची इस बात की गवाह है कि यदि कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवारों का विशेष ध्यान रखा है, तो जनता दल की सूची में राजपूतों का आधिपत्य है। जातिगत आधार पर राजनीतिक समीकरण जोड़नेवाले पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस चुनाव में यदि कांग्रेस ब्राह्मण, हरिजन और मुसलमानों की परंपरागत धुरी को और मजबूत करना चाहती है, तो जनता दल राजपूत, जाट और पिछड़ी जातियों को मूल आधार बना रहा है। मुस्लिम वोट को भी इस समीकरण के साथ जोड़ने के लिए जनता दल ने अंतिम समय तक पूरी ताकत लगा दी। अपने निकटस्थ आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू की नाराजगी मोल लेने के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह का बार-बार शाही इमाम और सैयद शहाबुद्दीन से मिलने की कोशिश करना, तमाम तकरारों के बाद भी इंसाफ पार्टी से जनता दल का समझौते का प्रयास और उत्तर प्रदेश में नकवी को टिकट देना इसके साफ संकेत हैं।

ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट को अपनी ओर खींचने की जनता दल की कोशिश की कांग्रेसी शिविर को जानकारी नहीं थी। देश के इस १३ फीसदी वोट बैंक को मजबूती से पकड़े रखने के लिए कांग्रेस इसीलिए उत्तर प्रदेश व बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित कर और उर्दू अकादमियों व वक्फ बोर्ड के अनुदान बढ़ा कर उनकी मार्फत अपनी पकड मजबूत करने और भाजपा-जनता दल के गठबंधन को उछालकर मुस्लिम मतों को विपक्ष से दूर रखने की रैणनीति को ही आगे बढ़ाती रही है।

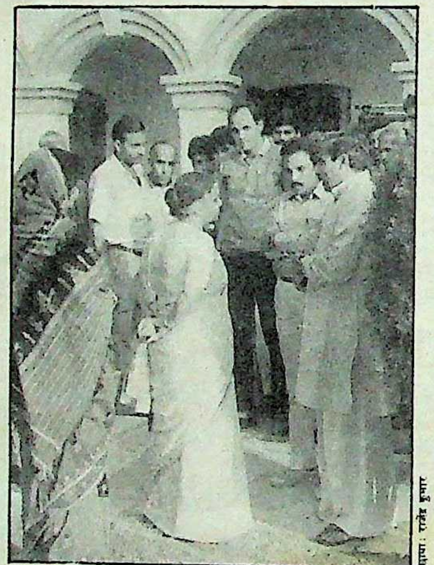
छाया : राजेश कुमार

मोर्चे संभालने के निर्देश : शीला दीक्षित

अपने किले की मोर्चाबंदी के लिए ही कांग्रेस ने हाल में वयोवृद्ध नेता कमलापति त्रिपाठी की भी मान-मनुहार की। इसकी भी रणनीति दोहरी है। एक, पुराने कांग्रेसियों का मन मोहना, दूसरे ब्राह्मणों को रिझाना-पटाना। उल्लेखनीय है कि संसदीय दल की बैठक में कमलापति त्रिपाठी पहले तो स्वयं नहीं आये और जब उन्हें मनाने राजीव गांधी के दूत बनकर माखनलाल फोतेदार पहुंचे, तो भी पंडितजी अड़े रहे। हारकर स्वयं राजीव गांधी को उनके घर जाकर ४५ मिनट बिताने पड़े।

टिकैत पर डोरे: एक ओर दोनों पक्ष जातिगत समीकरण बिठाने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर सर्वाधिक बड़े मतदाता वर्ग किसानों को रिझाने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गयी। कांग्रेस ने इसके लिए दो मुख्य रास्ते चुने। एक, पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री

आठवीं लोकसभा के कीर्त्तिमान

लोकसभा में पहली बार कांग्रेस-इ के ४०५ सांसद पहुंचे। १९८४ के आम चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त मतों का प्रतिशत ५०.०१ था। इसके पूर्व कांग्रेस को सर्वाधिक मत ४७.७८ प्रतिशत और सर्वाधिक ३७१ स्थान १९५७ में प्राप्त हुए थे।

पांच वर्षों में लोकसभा ४८५ दिन बैठी और ३२२७ घंटे कामकाज चला। पांचवें सत्र में सर्वाधिक ३५९ घंटे १८ मिनट तथा सबसे कम २१ घंटे काम १४वें सत्र के दूसरे भाग में हुआ। सबसे लंबा सत्र १९८७ का बजट सत्र था जो ५० दिन चला, तथा सबसे छोटा सत्र अंतिम सत्र था जो सिर्फ तीन दिन चला। स्मरणीय है कि अकेले बोफोर्स विवाद पर आठवीं लोकसभा में ५८ घंटे चर्चा हुई।

इस बीच २३ सांसदों की मृत्यु हुई जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

बोफोर्स दलाली-घोटाले को लेकर भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार १०१ विपक्षी सांसदों ने संसद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। इस प्रकार आठवीं लोकसभा के समापन के समय संसद विपक्ष शून्य हो चुकी थी।

आठवीं लोकसभा के सांसद इस मायने में खुशनसीब हैं कि सभी को पांच सौ रुपए प्रतिमास की पेंशन मिलेगी।

आठवीं लोकसभा ने संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। इन संविधान संशोधन विधेयकों में पंचायती राज, दलबदल विरोधी विधेयक, दंड विधि संहिता विधेयक तथा 'मुस्लिम पर्सनल ला' विधेयक प्रमुख हैं।

आठवीं लोकसभा में ४२० निजी विधेयक प्रस्तुत हुए, जिनमें से ३४२ अभी भी विचाराधीन हैं। केवल ५३ बिल पारित हुए,

२० वापस लिये गये तथा पांच बिलों को सदन ने अस्वीकृत कर दिया।

आठवीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान ९८ हजार सवाल पूछे गये, जिनमें से ९०४६ सवाल तारांकित थे, जिनका जवाब मंत्रियों को मौखिक रूप से देना होता है, ८९२८१ सवाल अतारांकित थे तथा केवल १८ सवाल अल्पकालिक सूचना पर पूछे गये थे। सर्वाधिक १२०२६ सवाल लोकसभा के दसवें सत्र में, सबसे कम ४९३ सवाल सदन के प्रथम सत्र में पूछे गये थे।

आठवीं लोकसभा के समूचे कार्यकाल के दौरान विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ पांच अविश्वास प्रस्ताव रखे। इनमें दो अविश्वास प्रस्ताव आठवीं लोकसभा के दूसरे सत्र (१३ मार्च से २० मई, १९८५) में तथा तीन संसद के नौवें सत्र (६ नवंबर से १५ दिसंबर, १९८७) में प्रस्तुत हुए, लेकिन केवल एक अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए स्वीकृत (नौवें सत्र में) हुआ और बहस के बाद गिर गया।

करीब एक दर्जन से अधिक कांग्रेस सांसदों को भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल बनाये जाने के कारण लोकसभा छोड़नी पड़ी।

आठवीं लोकसभा में ३४४ सरकारी विधेयक पारित किये गये। तीन विधेयक ऐसे थे, जिन्हें सदन के पटल पर रखने के बाद वापस ले लिया गया। आठवीं लोकसभा के दसवें सत्र में ३४ बिल पारित हुए जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसे उलटने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इस तरह निष्प्रभावी बनाने की घटना भी भारत के संसदीय इतिहास में पहली दफा हुई।

१९८७ के बजट सत्र में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत ५६८८ करोड़ रु० घाटे का वार्षिक बजट आजाद भारत का सर्वाधिक घाटे का बजट था।

उड़ीसा की चिंता छोड़िए: बीजू पटनायक

छाया : सुनील सक्सेना

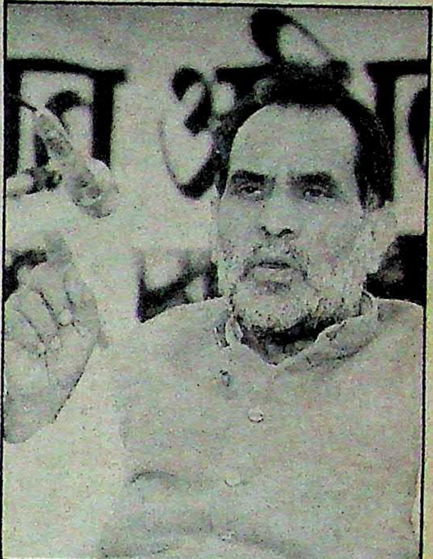

लड़ाई सिद्धांतों की है: चंद्रशेखर

राजेश पायलट के नेतृत्व में फिर से खड़े किये गये अपने किसान सेल की मार्फत कस्बा स्तर के किसान नेताओं और सहकारिता संगठनों द्वारा किसान वोटों को मजबूत करना। दूसरे, किसी तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत को पकड़ना। दिल्ली में हाल में हुई किसान पंचायत में कांग्रेस को इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। ज्ञात रहे, इस बीच विपक्ष ने शेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी पर डोरे डाले थे। नतीजा सामने था और दिल्ली की ऐतिहासिक किसान पंचायत जूतमपैजार में शुरू होने से पहले ही टूट गयी।

इससे आशान्वित हो कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक जोरदार प्रयास यह किया कि किसी भी तरह महेंद्र सिंह टिकैत और उनकी किसान यूनियन को चुनाव में उतरने के लिए तैयार कर लिया जाये। कांग्रेसी मोर्चाबंदी के शिल्पकारों का मानना था कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन चुनाव लड़े, तो चौधरी चरण सिंह का परंपरागत जाट और किसान वोट टिकैत और अजीत सिंह के बीच बराबर बंट कर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ कर देगा। टिकैत के कांग्रेसी समर्थक-सलाहकारों की लाबी ने जोर मारा और १७ अक्तूबर की रात टिकैत अपने पैर में चोट लगे होने के बावजूद खासे गुपचुप ढंग से दिल्ली पहुंचे। पूरी रात और अगले दिन सुबह चली वार्ताओं का नतीजा था कि टिकैत इसके लिए तैयार हो गये कि किसान यूनियन अपना अराजनीतिक चरित्र छोड़कर चुनावी अखाड़े में उतरे। तय हुआ कि २३ अक्तूबर को एटा में होने वाली किसान यूनियन की पंचायत में ही इसका फैसला कर घोषणा कर दी जायेगी। इसके लिए यूनियन के दूसरे जिलों के भी लगभग हर महत्वपूर्ण प्रधान को तार भेज दिये गये कि वे भी एटा पहुंच जायें।

पर तब तक यूनियन में मौजूद कांग्रेस विरोधी धड़ा सतर्क हो चुका था। २३ अक्तूबर को एटा में पंचायत शुरू होने से पहले ही टिकैत से मिलनेवाले प्रधानों के तेवर पहली दफा बदले हुए थे। अधिकतर का कहना था, "वे यूनियन के लिए सब कुछ दे सकते हैं, पर वोट तो वे चौधरी चरण सिंह के बेटे को ही देंगे।" प्रधानों का यह रुख और यूनियन की कांग्रेसी विरोधी लाबी के भारी दबाव को देखने के बाद ऐन वक्त पर टिकैत को अपना फैसला बदलना पड़ा और कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण मोर्चाबंदी धरी की धरी रह गयी।

कांशीराम की मनुहार: हरिजनों को भी अपने पाले में रखने के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों ही चालें चलते रहे। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से परिवर्तनशील मोर्चे तक की यात्रा तय किये बसपा अध्यक्ष कांशीराम मुख्य लक्ष्य रहे। प्रयास नामांकन के अंतिम क्षणों तक चले। कांशीराम ने 'माया' को बताया, "अमेठी से राजमोहन गांधी का नाम घोषित करने की पूर्व संध्या, २६ अक्तूबर की रात जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ० देवीलाल ने दिल्ली के पुराने सचिवालय के पीछे कैनाल गेस्ट हाउस में मुझसे गुपचुप भेंट की। उनका आग्रह था कि मैं अमेठी से राजीव गांधी के विरुद्ध उम्मीदवार बनूं। दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया कि संपूर्ण विपक्ष मुझे अपना पूर्ण समर्थन देगा।" किंतु कांशीराम 'सोचेंगे' कह कर चले आये।

इसकी भनक पाते ही कांग्रेस सक्रिय हो उठी। फौरन ही देर रात राजीव गांधी की ओर से कांशीराम से बात करने के लिए राजेश पायलट को दौड़ाया गया। मकसद कांशीराम को संशय में डाल विपक्ष से अलग-थलग किये रखना था। पायलट को कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली। अगली सुबह तक कांशीराम अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में कोई भी फैसला करने में

असमर्थ रहे। उसी सुबह 'माया' से हंसते हुए बोले, "सांपनाथ और नागनाथ के बीच नेवला (बसपा) मजा ले रहा है।" कांशीराम की इसी मानसिकता के चलते दोपहर तक उनके शिविर से कोई सूचना न मिलने के बाद विपक्ष को गांधी (राजीव) के खिलाफ महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी का नाम घोषित करना पड़ा। इसके अड़तालीस घंटे के भीतर ही अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करके कांशीराम ने कांग्रेस और विपक्ष दोनों को चौंका दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार कांशीराम का यह नामांकन न केवल अमेठी, बल्कि आसपास की काफी लोकसभा सीटों पर हरिजनों के मत को प्रभावित करेगा।

नाटकीय नामांकन : नामांकन को लेकर भी दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी मोर्चाबंदी की।

छाया : सुनील सक्सेना

बागपत तो जीता हुआ है, मगर आगे.. अर्जीत सिंह

कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने नाटकीय ढंग से सबसे पहले अपना नामांकन दाखिल कर विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए अपने पार्टीजनों का मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया। इसके विपरीत जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आखिरी समय तक अपने पत्ते छिपाये रखकर कांग्रेस को सांसत में डाले रखना बेहतर समझा। किंतु यही रणनीति तब खुद वीपी सिंह की सांसत का कारण बन गयी, जब नामांकन के अंतिम दिन ३० अक्तूबर को दिल्ली से फतेहपुर के लिए रवाना हो रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के विमान की उड़ान तीन दफा रद्द की गयी। पहली बार तो सिंह का विमान दिल्ली से उड़कर लगभग लखनऊ के पास से वापस ले आया गया। कभी विमान में बम होने, तो कभी तकनीकी बहाना बनाकर बार-बार सिंह को जाने से रोका जाता रहा। उनके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल द्वारा भेजे गये राज्य सरकार के विमान को भी तकनीकी बहाने बनाकर उड़ने से रोक दिया गया। अन्त में वायुदूत के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन द्वारा हस्तक्षेप पर सिंह को दिल्ली से सीधे कानपुर विमान भेज कर पहुंचाया गया। कानपुर से अंतिम क्षणों में बदहवास दौड़ता सिंह की कारों का लंबा काफिला नामांकन खतम होने के बमुश्किल बारह मिनट पहले फतेहपुर पहुंच नामांकन दाखिल कर पाया।

श्री सिंह की अंतिम क्षणों तक रुके रहने की रणनीति सरकार द्वारा उठाये अप्रत्याशित कदम से निश्चय ही कारगर सिद्ध हुई। आम जनता सिंह के मार्ग में इस अड़ंगेबाजी को नाजायज और अलोकतांत्रिक तो मान ही रही है, साथ ही कांग्रेस शिविर में दिनोदिन गहराती हताशा-निराशा का द्योतक भी करार दे रही है। इसका राजनीतिक लाभ निश्चित तौर पर विपक्ष के खाते में जायेगा।

> पंत का धमाका क्या गुल खिलायेगा, इसका जवाब तो सिर्फ भारतीय मतदाता के पास है। पर मतदान के दिन तक इस तरह के अभी तमाम धमाकों का पक्ष और विपक्ष दोनों को इंतजार है।

पंत की 'बगावत' : दीपावली के दूसरे दिन घटी एक अन्य घटना भी विपक्ष के लिए तब शुभ संदेश, संकेत लायी, जब केंद्रीय रक्षा मंत्री कृष्ण चंद्र पंत ने यकायक दो सीटों पर नामांकन भरने के आलाकमान के आदेश को सार्वजनिक रूप से ठुकराते हुए प्रधानमंत्री के चारों ओर एकत्र 'काकस' के विरुद्ध बगावत का झंडा उठा लिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार ऐसा कर पंत ने अपनी संभावित दोहरी हार—आंवला में यदि मुख्यमंत्री तिवारी उन्हें हरवाते, तो नयी दिल्ली में क्रुद्ध जनता पिछले चुनाव के बाद से अपने सांसद को देखने के लिए तरसती रही है—के अपमान से तो अपनी रक्षा कर ली है, किंतु कांग्रेसी किले को और असुरक्षित कर दिया है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि शुरू से ही कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के लिए रक्षामंत्री संकट-सांसत खड़ा करते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए १९६२ में चीनी हमले के बाद कृष्ण मेनन सिरदर्द बन गये थे। श्रीमती गांधी के शासनकाल में १९७७ में रक्षामंत्री जगजीवन राम ने इस्तीफा देकर जनता पार्टी को सत्तारूढ़ कराने में भरपूर सहायता की थी। राजीव गांधी के पूर्व रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह और यहां तक कि पहली बार जब गृह मंत्रालय में आंतरिक रक्षा राज्य मंत्री का पद बना, तो इसके सर्वेसर्वा अरुण नेहरू ने बारी-बारी भंडाफोड़ कर और इस्तीफे देकर सांसत खड़ी कर दी थी।

पंत का धमाका क्या गुल खिलायेगा, इसका जवाब तो सिर्फ भारतीय मतदाता के पास है। पर मतदान के दिन तक इस तरह के अभी तमाम धमाकों का पक्ष और विपक्ष दोनों को इंतजार है। चाहे बोफोर्स के नये रहस्योद्घाटन हों या विपक्षी नेताओं पर कांग्रेसी शिविर से लगनेवाले एक के बाद एक नये आरोप हों। दोनों ओर की इस मोर्चाबंदी और 'गोलाबारी' का असली मोर्चा ९ और १० नवंबर को अयोध्या में होनेवाला रामशिलापूजन महायज्ञ और राम मंदिर शिलान्यास समारोह होगा।

मैं स्थायी सरकार दे सकता हूं : हेगड़े

इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष द्वारा अपनाया रुख बाजी को निर्णायक मोड़ पर ले जायेगा। और तब दोनों खेमे अपने-अपने तुरुप के पत्तों के रूप में 'हिंदू' और 'मुस्लिम कार्ड' निकालें, तो आश्चर्य नहीं। यही वह नाजुक मोर्चा भी होगा, जिस पर भाजपा और वाममोर्चा के बीच जैसे-तैसे संतुलन बनाये जनता दल को एक बार फिर परीक्षा की कड़ी कसौटी पर खरा उतरना होगा। उधर एक साथ 'हिंदू कार्ड' और 'मुस्लिम वोट बैंक' दोनों को आकर्षित करने की रणनीति में झूलती कांग्रेस को अपनी पारी तय करनी होगी। क्योंकि दोनों ही पत्तों को एक साथ खेलने का खतरनाक और दुष्कर मार्ग खोज पाना यदि असंभव नहीं, तो बेहद कठिन जरूर है। इस मोर्चे पर पक्ष-विपक्ष द्वारा अपनाया गया रुख जहां एक तरफ अगले चुनावों का फैसला करेगा, वहीं उनके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम उनकी राजनीतिक रोटियां भले ही सिकवा दे, हजारों घरों के चूल्हे जरूर बुझा देगा।—**रंजना कक्कड़,**

पुनीत टंडन, त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

काम से लौट कर... हँसी-खुशी के पल !

ज़िन्दगी की भागदौड़, और दफ़्तर में काम का दबाव। पर शाम घर लौटने पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और आपके पति बच्चों के संग उत्साह और उमंग के साथ व्यस्त हो जाते हैं।

इसका श्रेय आपको है। क्योंकि आप दिन-भर चुस्ती और शक्ति के लिए उन्हें रोज़ हॉर्लिक्स जो देती हैं।

"हॉर्लिक्स में अत्यंत आवश्यक पोषक तत्त्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ—होते हैं जो शरीर को शक्ति, चुस्ती और तन्दुरुस्ती देते हैं। दिन-भर अच्छे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर बने रहने के लिए।"

Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nourisher
PROTEINS
VITAMINS
MINERALS
CARBOHYDRATES
CALCIUM ENRICHED
EASY TO DIGEST
ENERGY SOURCE
COMPLETELY NATURAL

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6224 HIN

सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी

प्रधानमंत्री के पद के दो ही व्यक्ति सशक्त दावेदार हैं—राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह।

जनता दल की स्थापना वृश्चिक लग्न में हुई थी। लग्नेश मंगल पंचम भाव में वृहस्पति की राशि में है जो केतु और शुक्र से षडाष्टक योग बना रहा है। द्वितीय भाव में शनि है जो वृहस्पति से षडाष्टक योग बना रहा है। चतुर्थ भाव में राहु है जो सूर्य-चंद्र-बुध से षडाष्टक योग बना रहा है। सभी ग्रह षडाष्टक योग बना रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुण्डली में सभी ग्रह षडाष्टक योग बनाते हैं, तो सफलता-असफलता के बीच अंतर कम होता है। जब किसी संस्था की कुण्डली में सभी ग्रह षडाष्टक योग बनाते हैं, तो वह संस्था भी असफलता और संघर्ष तथा सफलता के घेरे में आंख मिचौली करती रहती है। ऐसा ही जनता दल की कुण्डली में है। जनता दल के यहां सभी ग्रह षडाष्टक योग बना रहे हैं, वहीं द्वितीयेश और पंचमेश वृहस्पति २१ जुलाई, १९९० तक आठवें भाव में रहेगा। जो पार्टी को प्रभावी तो बनायेगा, लेकिन सत्ता में नहीं आने देगा। जब पार्टी ही सत्ता में नहीं आयेगी, तो पार्टी का प्रत्याशी कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है?

मीन लग्न में २८ दिसंबर, १८८५ को कांग्रेस की स्थापना हुई। लग्नेश वृहस्पति सप्तम भाव में चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। शत्रु भाव में राहु मंगल की युति है जो विपक्ष को नुकसान देनेवाली है। वर्तमान में शुक्र महादशा में वृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। वृहस्पति राहु से षडाष्टक योग बना रहा है। यह योग कांग्रेस को पुनः सत्ता में रखेगा। यद्यपि विगत लोकसभा की शक्ति में कमी आयेगी।

२२ नवंबर को होनेवाले चुनाव पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रारंभ होंगे। सूर्य-बुध वृश्चिक में, शुक्र-शनि धनु में, मकर में राहु, गुरु मिथुन में, केतु-कर्क में, सिंह में चंद्रमा, तुला में मंगल, बुध अस्त, गुरु वक्री, सूर्य-बुध वृहस्पति से षडाष्टक योग, शुक्र-शनि केतु से षडाष्टक योग, राहु वृहस्पति तथा चंद्र से षडाष्टक योग बना रहा है। मंगल को छोड़कर सभी ग्रह षडाष्टक योग बना रहे हैं। मंगल अपनी राशि और सूर्य से बारहवें स्थान पर है, जिस कारण चुनाव में हिंसा तथा खून-खराबा होगा। चुनाव परिणाम अत्यधिक आश्चर्यजनक होंगे। अनेक दिग्गज राजनेता तथा कई महत्वपूर्ण सांसद या मंत्री पराजित होंगे। सिंह राशि का चंद्रमा दसम भाव में है। जो राहु से षडाष्टक योग बना रहा है। चंद्रमा से तीसरे भाव में मंगल है। यह ग्रह स्थिति

जनता दल प्रभावी होगा

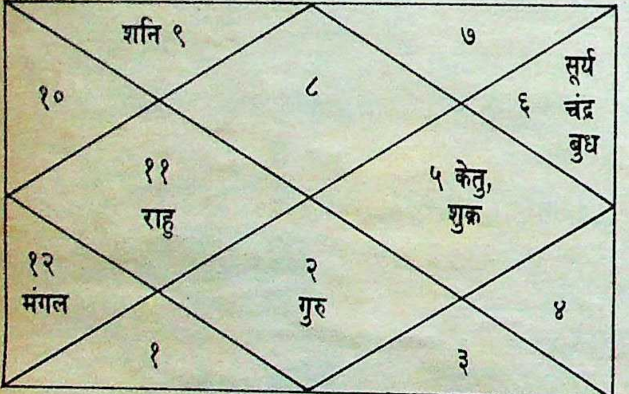
शनि ९
७
१०
८
६
सूर्य
चंद्र
बुध
११
राहु
५ केतु,
शुक्र
१२
मंगल
२
गुरु
४
१
३

सरकार तो कांग्रेस ही बनायेगी

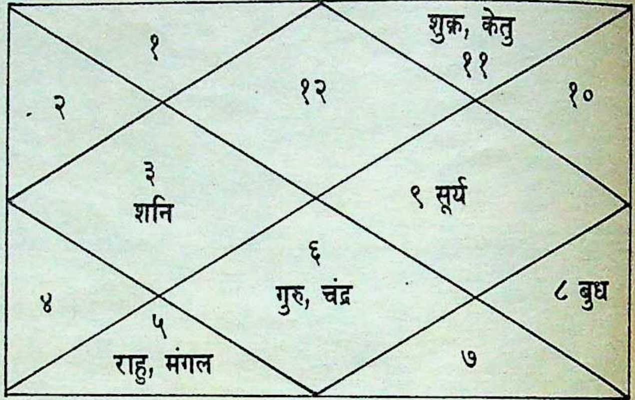
१
शुक्र, केतु
११
१२
१०
२
३
शनि
९ सूर्य
६
गुरु, चंद्र
४
८ बुध
५
राहु, मंगल
७

२२ नवंबर '८९ की ग्रह-स्थिति

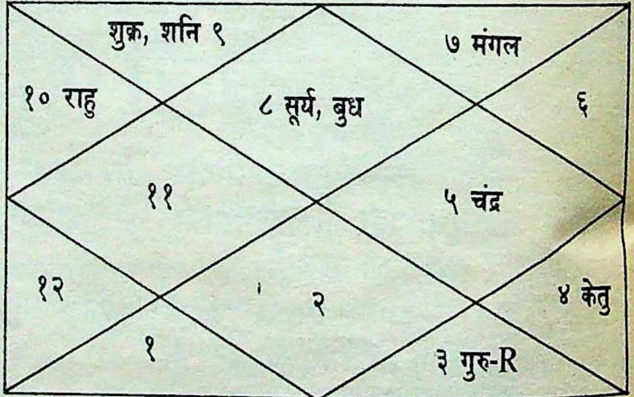
शुक्र, शनि ९
७ मंगल
१० राहु
८ सूर्य, बुध
६
११
५ चंद्र
१२
२
४ केतु
१
३ गुरु-R

राजीव गांधी

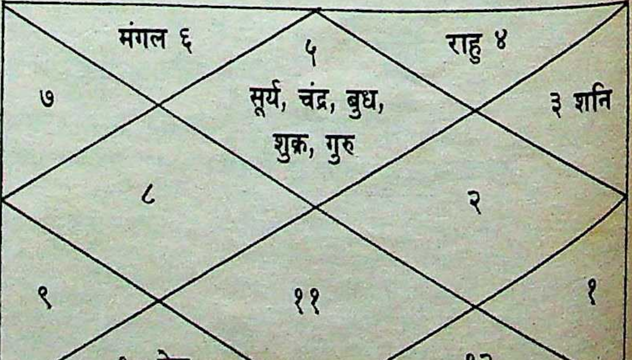
मंगल ६
५
राहु ४
७
सूर्य, चंद्र, बुध,
शुक्र, गुरु
३ शनि
८
२
९
११
१
१० केतु
१२

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए उत्तम है। २२ नवंबर को हुए मतदान में कांग्रेस को विशेष सफलता मिलेगी।

२४ नवंबर को सूर्य बुध-वृश्चिक में, शनि शुक्र-धनु में, राहु मकर में, गुरु मिथुन में, केतु कर्क में, चंद्रमा कन्या में, मंगल तुला में, बुध अस्त, गुरु वक्री। सूर्य-बुध-गुरु से षडाष्टक योग, शनि-शुक्र-केतु से षडाष्टक योग तथा राहु-गुरु से षडाष्टक योग बना रहा है। चंद्रमा और मंगल किसी से भी षडाष्टक योग नहीं बना रहा है। चंद्रमा-बुध की राशि कन्या में, उसका स्वामी बुध अस्त है जो सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायी है। सत्ता पक्ष के कई महत्वपूर्ण नेता पराजित होंगे। चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। विपक्ष के लिए २४ नवंबर की तिथि अधिक सहायक होगी, जबकि २२ नवंबर को होनेवाले निर्वाचन में कांग्रेस को अधिक लाभ मिलेगा। दोनों तिथियों को होनेवाले निर्वाचन की गणना के अनुसार ही सरकार कांग्रेस की ही बनेगी।

२४ नवंबर, ८९ की ग्रह-स्थिति

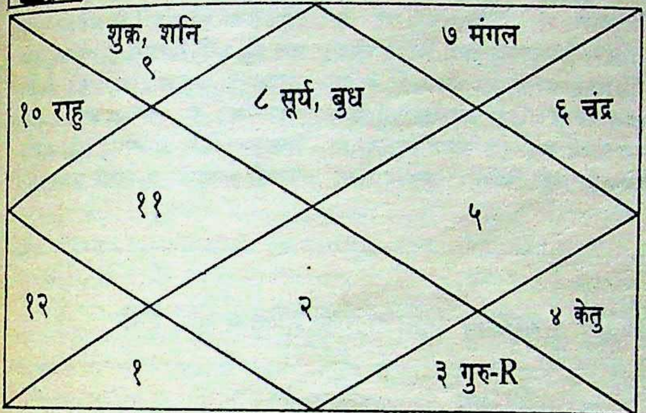
शुक्र, शनि
९
७ मंगल
१० राहु
८ सूर्य, बुध
६ चंद्र
११
५
१२
२
४ केतु
१
३ गुरु-R

राजीव गांधी की जन्म कुण्डली के कई लग्न अलग-अलग विद्वान मानते हैं। मैंने उनके सिंह लग्न को स्वीकारा है। मई १९८४ के 'माया' अंक में प्रकाशित भविष्यवाणी—"राजीव गांधी की कुण्डली प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम है, लेकिन श्रीमती गांधी की कुण्डली का ग्यारहवें भाव का गुरु बाधा उत्पन्न करेगा। श्रीमती गांधी के जीवन के पश्चात राजीव गांधी का भविष्य अधिक उज्ज्वल होगा। अपने पौरुष एवं योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करने में सफल होंगे। वे एक सशक्त व्यक्ति के रूप में लोकसभा में आयेंगे। भारी मतों से विजयी होंगे।"

ठीक ऐसा ही हुआ, 'माया' के चुनाव विशेषांक में भी। जो भविष्यवाणियां की गयी थीं, वे भी पूरी तरह से सत्य घटित हुईं। उसका आधार राजीव गांधी का सिंह लग्न था। इससे स्पष्ट होता है कि राजीव गांधी का लग्न सिंह ही है। सिंह लग्न के जातक का भाग्योदय ४१ वर्ष की आयु में होता है। ४१ वर्ष की ही आयु में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इससे सिंह लग्न की पुष्टि और अधिक होती है। चुनाव के समय मंगल उदय होगा और वह मंगल राजीव गांधी को सफलता देगा। राहु में बुध की अंतरदशा चल रही है। इन दिनों आकाश में बुध अस्त रहेगा, जिस कारण संसद में विगत लोकसभा की सदस्य संख्या में कमी आयेगी, फिर भी वे सरकार बनाने में सफल होंगे। राजीव गांधी ही पुनः प्रधानमंत्री होंगे।

जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है। लग्नेश चंद्र की अंतरदशा बुध महादशा में चल रही है जो २५ दिसंबर, १९९० तक रहेगी। जिस दिन से चंद्रमा की अंतरदशा प्रारंभ हुई है, उस दिन से उन पर तरह-तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं। चुनाव के समय बुध अस्त होगा जो उनके प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने में बाधक होगा। चंद्रमा और बुध आपस में शत्रुता रखते हैं। बुध में चंद्रमा की अंतरदशा प्रधानमंत्री पद के लिए बाधक है। ग्रह स्थिति उनके विपरीत है, जिस कारण संसद में सांसदों की

विश्वनाथ प्रताप सिंह

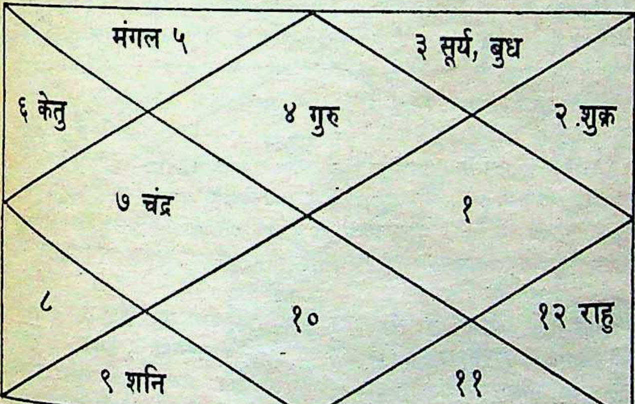
मंगल ५
३ सूर्य, बुध
६ केतु
४ गुरु
२ शुक्र
७ चंद्र
१
८
१०
१२ राहु
९ शनि
११

देवीलाल

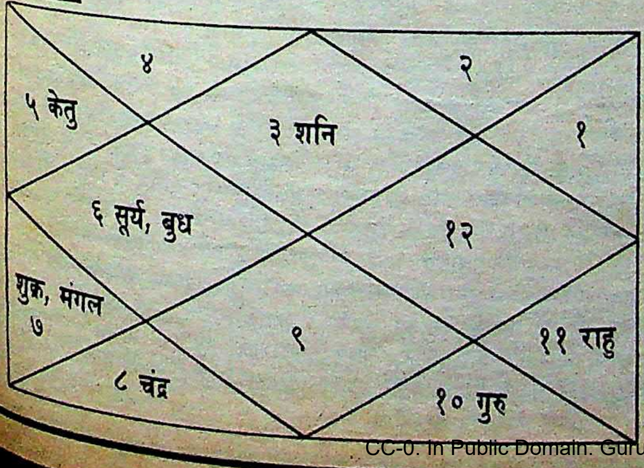
४
२
५ केतु
३ शनि
१
६ सूर्य, बुध
१२
शुक्र, मंगल
७
९
११ राहु
८ चंद्र
१० गुरु

चंद्रशेखर

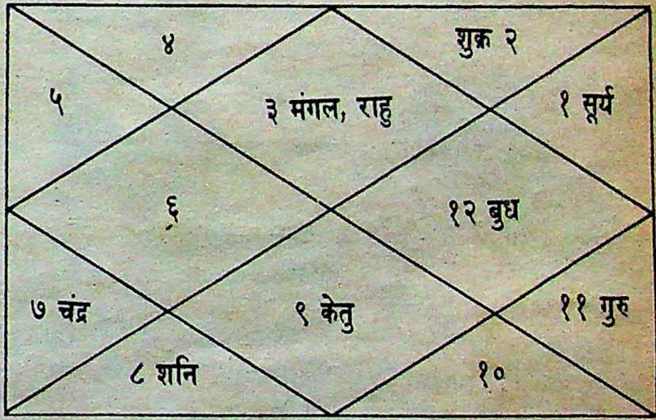
४
शुक्र २
५
३ मंगल, राहु
१ सूर्य
६
१२ बुध
७ चंद्र
९ केतु
११ गुरु
८ शनि
१०

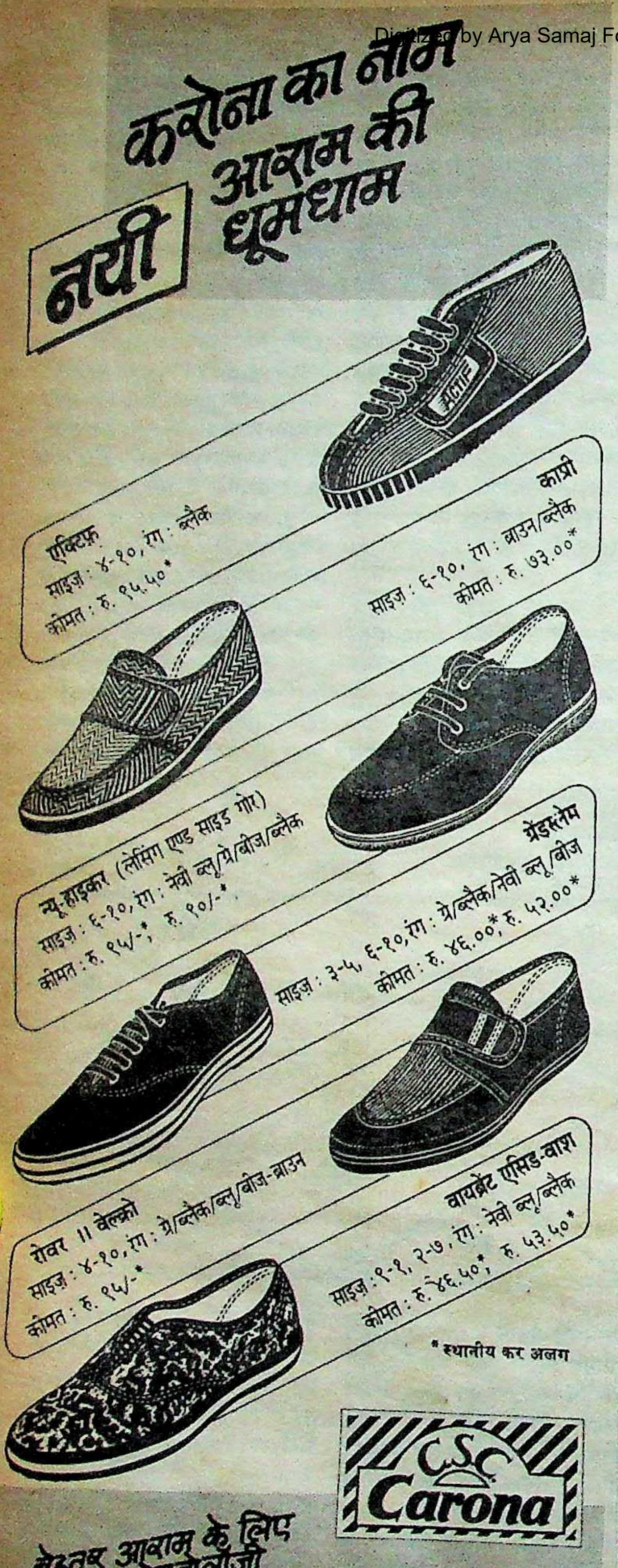
करोना का नाम
नयी
आराम की धूमधाम
एक्टिफ़
साइज़ : ४-१०, रंग : ब्लैक
कीमत : रु. ९५.५०*
काप्री
साइज़ : ६-१०, रंग : ब्राउन/ब्लैक
कीमत : रु. ७३.००*
न्यू-हाइकर (लेसिंग एण्ड साइड गोर)
साइज़ : ६-१०, रंग : नेवी ब्लू/ग्रे/बीज/ब्लैक
कीमत : रु. ९५/-*, रु. ९०/-*
ग्रैंडस्लैम
साइज़ : ३-५, ६-१०, रंग : ग्रे/ब्लैक/नेवी ब्लू/बीज
कीमत : रु. ४६.००*, रु. ५२.००*
रोवर ।। वेल्क्रो
साइज़ : ४-१०, रंग : ग्रे/ब्लैक/ब्लू/बीज-ब्राउन
कीमत : रु. ९५/-*
वायब्रेंट एसिड-वाश
साइज़ : ९-१, २-७, रंग : नेवी ब्लू/ब्लैक
कीमत : रु. ४६.५०*, रु. ५३.५०*
* स्थानीय कर अलग
CSC
Carona
बेहतर आराम के लिए
उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी

सभी करोना तथा प्रमुख फुटवेअर स्टोर्स में उपलब्ध

अच्छी संख्या होने पर भी वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। यद्यपि मंगल का उदय हो जाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। वे अनेक स्थानों पर कांग्रेस को भारी नुकसान देने में सफल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद का सपना फिलहाल पूरा न होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ। लग्नेश बुध चुनाव के समय अस्त रहेगा। जिस कारण उन्हें उस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी। यद्यपि लग्न में स्थित शनि, चंद्रमा और वृहस्पति से षडाष्टक योग बन रहा है। जिसने उन्हें इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाया है। उन्हें अभी और लोकप्रियता मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री पद की कोई संभावना नहीं।

जनता दल के महत्वपूर्ण राजनेता चंद्रशेखर का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। लग्न में मंगल राहु की युति है। लग्नेश बुध इन दिनों अस्त रहेगा। बुध की महादशा भी चल रही है और वह बुध आकाश में अस्त है। उनकी तुला राशि है, राशि से बारहवें स्थान पर चंद्रमा रहेगा, लग्न में वृहस्पति आठवें भाव में गोचर में राहु होगा जो षडाष्टक योग बना रहा है। वह स्थिति भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। अतः चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद से तो दूर रहेंगे ही।

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म तुला लग्न में हुआ है। लग्नेश शुक्र-सूर्य-केतु-शुक्र के साथ तृतीय भाव में है। सिंह राशि का चंद्रमा अकेला केमद्रुम योग बना रहा है। जहां यह केमद्रुम योग लोकप्रियता दे रहा है, वहीं प्रधानमंत्री पद के लिए घातक भी है। वाजपेयी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को विगत सभी लोकसभा की सीटों से अधिक अपने दल को सीटें दिलाने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा में सम्मानजनक होगी जिसका श्रेय वाजपेयी को होगा। उनकी कुण्डली में अभी प्रधानमंत्री पद का योग नहीं है।

रामकृष्ण हेगड़े, एनटी रामाराव, अरुण नेहरू तथा ज्योति बसु एवं अजीत सिंह की जन्मकुण्डली में प्रधानमंत्री पद का योग नहीं है, लेकिन रामाराव और ज्योति बसु अपने-अपने प्रदेश का नेतृत्व संभालने में सफल होंगे।

देश की ग्रहस्थिति तथा पार्टियों की ग्रह स्थिति, मतदान की तिथियां और राजनेताओं की ग्रह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस पुनः सरकार बनाने में सफल होगी। यद्यपि लोकसभा में उसकी सदस्य संख्या घटेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। अनेक दिग्गज नेता पराजित होंगे। कई स्थानों पर खून-खराबा होगा। चुनाव परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक होंगे।

—केए दुबे पद्मेश

भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में वृद्धि होगी

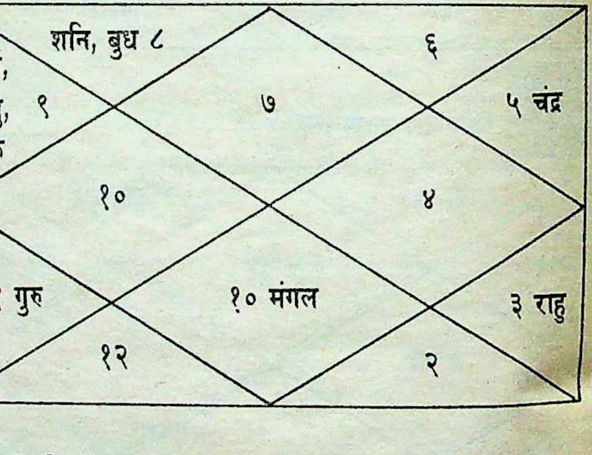
शनि, बुध ८
६
सूर्य, केतु, शुक्र ९
७
५ चंद्र
१०
४
११ गुरु
१० मंगल
३ राहु
१२
२

महंगाई कांग्रेस को मारेगी ?

बोफोर्स के बाद चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई। १९८० में कांग्रेस-इ ने मात्र प्याज के दाम को मुद्दा बनाकर अपना चुनाव अभियान छेड़ा था और उसका खासा असर भी पड़ा था। किंतु इस बार—पिछले चार महीनों—में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों ने जिस ढंग से आकाश छुआ है उसको देखते हुए क्या कांग्रेस-इ वोट मांगने की स्थिति में है ?

यदि १९८० में प्याज की बढ़ी कीमतें जनता पार्टी की हार का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती थीं, तो २२ नवंबर ८९ को होने वाले नौवीं लोकसभा के चुनाव में भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के आसमान छूते दाम राजीव गांधी की चुनावी पराजय का एक अहम कारण बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार मुद्दा प्याज के बजाय बंधगोभी, आलू, चीनी अथवा खाने का तेल होगा। यहां पर इस बात का उल्लेख अत्यंत जरूरी है कि जरूरत की चीजों के बढ़े हुए दाम से चुनाव पर कोई मामूली असर नहीं पड़ता। अलबत्ता सचाई तो यह है कि सिर्फ महंगाई ही सत्तारूढ़ दल को ३ से ५ प्रतिशत मतों की हानि पहुंचा सकती है। फिर ५४२ लोकसभा क्षेत्रों में से चौथाई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां मात्र ३ से ५ प्रतिशत मतों का हेर-फेर ही पार्टी के भविष्य को तय करता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री राजीव गांधी का महंगाई रोकने के प्रति सचेत न होना, निस्संदेह पार्टी तथा उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

१९८० का उदाहरण : कौन नहीं जानता कि १९८० के चुनाव से पूर्व प्याज के दामों पर ऐसी आफत आयी थी कि प्याज ७ रुपए प्रति किलो बिकने लगी थी। यही नहीं, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में भी चुनाव करीब आते-आते वृद्धि शुरू हो गयी थी तथा चरण सिंह और उनकी सरकार मतदाताओं में महंगाई को लेकर बढ़ते असंतोष पर काबू नहीं पा सकी थी। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात का दावा करती घूम रही थीं कि यदि उनकी सरकार बनी, तो प्याज पुनः २.५० रुपए प्रति किलो बिकेगी तथा जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। अंततः नतीजा क्या सामने आया ? यही न कि जनता पार्टी की हुकूमत चली गयी और कांग्रेस पुनः सत्ता में आयी। तो फिर क्या यह मानकर चला जाये कि इस बार भी सत्तारूढ़ दल के हाथ से सत्ता छिनने वाली है ? क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस सचाई को जानते हुए भी आखिर कर क्या सकते हैं ?

निस्संदेह राजीव गांधी महंगाई के चुनाव पर असर से भलीभांति परिचित हैं और खबरों से यह जाहिर भी हो रहा है कि वे आकाश छूती महंगाई से काफी विचलित भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को इस आशय का निर्देश भी दिया है कि वे किसी तरह भी महंगाई पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करें। राज्य सरकारों को भी आलाकमान से इसी तरह के आदेश प्राप्त हुए हैं। किंतु सवाल यह है कि आखिर बेचारी राज्य सरकारें कर क्या सकती हैं ? यही न कि उनके पास जो उपभोक्ता वस्तुएं मौजूद हों, उन्हें वे जल्दी से जल्दी बिक्री हेतु बाजार में पहुंचा दें, किंतु दामों पर नियंत्रण करना उनके वश की बात तो है नहीं !

सरकार असमर्थ : ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्र सरकार या राजीव गांधी महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कर क्या सकते हैं ? समाचारों में रुचि रखने वाला तबका भली भांति जानता है कि हाल में ही राजीव सरकार ने हिंदीभाषी क्षेत्रों के किसानों को खुश करने के लिए गेहूं की वसूली दर में १७ रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, यानी सरकार ने ही गेहूं पर प्रति किलो १७ पैसे की वृद्धि को वाजिब बनाया है। सरकार के इसी कदम ने गेहूं के व्यापारियों को खुले बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ाने को प्रोत्साहित किया है। जाहिर है, व्यापारियों को दाम बढ़ाने के लिए बेहतरीन तर्क मिल गया है कि जब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं २.७५ रुपए अथवा ३ रुपए प्रति किलो बेचा जा सकता है, तो बाजार में उससे अच्छा गेहूं ४.२५ रुपए अथवा ४.५० रुपए प्रति किलो क्यों नहीं बेचा जा सकता ? जाहिर है,

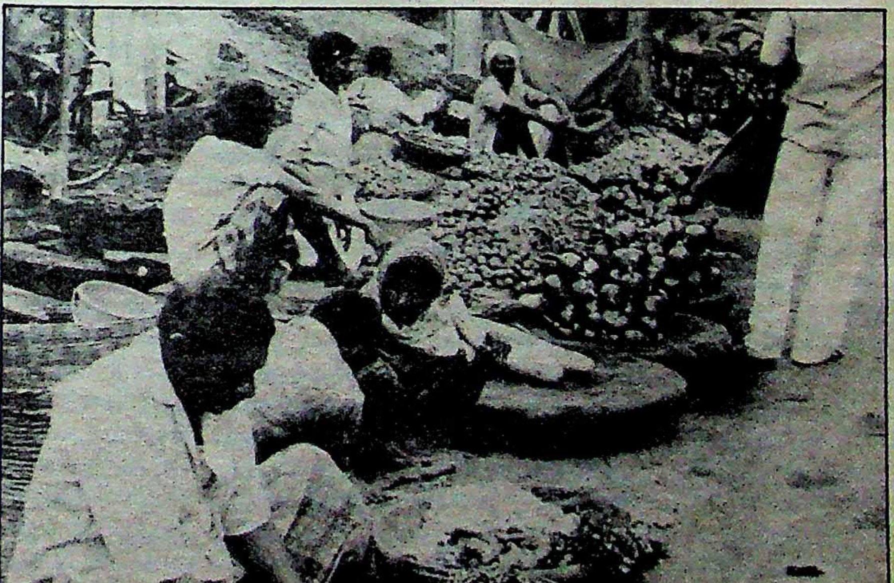

बिल्कुल यही हाल सब्जियों पर आयी महंगाई का है। आलू और प्याज, जिसका इस्तेमाल देश का लगभग हर परिवार किसी-न-किसी रूप में, थोड़ा या ज्यादा करता है उसकी कीमत भी काफी बढ़ गयी है।

कोई भी हरी सब्जी ४ रुपए प्रति किलो से कम में बाजार में उपलब्ध नहीं है। कुछ विशिष्ट सब्जियां जैसे बंदगोभी आदि तो ६ रुपए प्रति किलो से कम नहीं।

छाया : वसीमुल हक

नया गेहूं बाजार में अप्रैल '९० से पहले नहीं पहुंच सकता, इसलिए कीमत घटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता चुनाव के ऐन एक सप्ताह पूर्व भी 'अच्छे गेहूं' के नाम पर बाजार में गेहूं का दाम और चढ़ने की ही उम्मीद है।

यहां पर इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि बढ़ती महंगाई के लिए राजीव गांधी किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही हाल में गेहूं वसूली की दर में ९ प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया था। वह भी इसलिए क्योंकि उनका लक्ष्य पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग १.८० करोड़ किसानों को संतुष्ट करना था, ताकि २२ नवंबर को इस तबके का वोट उनकी झोली में गिरे। जाहिर है, जब नीति पक्षपातपूर्ण होगी, तो जहां एक पक्ष संतुष्ट होगा, वहीं दूसरा पक्ष नाराज। ऐसे में कांग्रेस को गेहूं खरीदनेवाले मतदाताओं का तो कोप सहन करना ही पड़ेगा।

आकाश छूती महंगाई : महंगाई बढ़ने के अन्य कारण भी हैं, किंतु वे आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इस पहेली को समझने के लिए सरकारी अनुमान तथा आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालनी होगी। सरकारी अनुमान के अनुसार १९८८-८९ में अन्न उत्पादन में ३.४० करोड़ टन की वृद्धि हुई तथा अन्न उपभोक्ता आबादी में १.६० करोड़ से अधिक की वृद्धि नहीं हुई। जाहिर है, लगभग १.६ करोड़ नये उपभोक्ता २५ लाख टन से अधिक अन्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में ३.१५ करोड़ टन अनाज तो 'न्यूनतम बेशी' के रूप में आगामी वर्ष १९८९-९० के खाते में आना चाहिए था। किंतु स्थिति यह है कि ८९-९० के लिए न्यूनतम बेशी के रूप में ३.१५ करोड़ टन अनाज का आना तो बड़ी बात है, देश की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार को अनाज आयात करने का निर्णय लेना पड़ा है। खबरों के अनुसार सरकार फिलहाल ४ लाख टन गेहूं का आयात कर चुकी है जिसमें देश को ९.५० करोड़ डालर के बराबर रुपए खर्च करने पड़े। ऐसे में क्या सरकारी आंकड़े अपने आप में एक पहेली नहीं ?

यही नहीं, अनाज की बचत और भंडारण तो और बात है, स्थिति यह है कि दिन-पर-दिन (देश में अतिरिक्त अन्न उत्पादन के बावजूद) अनाज की कीमतें चढ़ती ही जा रही हैं। सितंबर '८९ के अंत तक सरकार के फैसलों के परिणामस्वरूप मोटे चावल की थोक कीमत में ९ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी तरह गेहूं की थोक कीमत भी सरकारी निर्णयों से लगभग १५ प्रतिशत बढ़ी। नतीजतन गेहूं की दर ३४० रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर ३९२.५० रुपए प्रति क्विंटल हो गयी थी। हाल में किसानों को खुश करने के लिए जब सरकार ने सोचा, तो गेहूं की कीमत में जो इजाफा हुआ, उससे प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत पर १७ रुपए और बढ़ गये। इस सबकी परिणति यह हुई कि देसी आटा फुटकर में ४ रुपए प्रति किलो से कम में उपलब्ध नहीं है।

सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान

छाया : बसीमुल हक

सरकारी झूठ : अब आइये तस्वीर के दूसरे रुख पर नजर डालें कि सरकार ने किस मात्रा में अनाज वसूली की तथा पिछले सालों के मुकाबले इस साल की वसूली कम है या ज्यादा। आंकड़ों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि पिछले छह-सात सालों से सरकार प्रति वर्ष कुल अनाज उत्पादन का १० से १५ प्रतिशत भाग वसूल करती रही है। किंतु इस वर्ष सरकारी वसूली १० प्रतिशत से भी कम है। इस पर सरकारी सूत्रों का जवाब है कि किसान अपना उत्पादन सरकार के हाथ बेचने को तैयार नहीं हैं। वे अपना अनाज खुले बाजार में बेच रहे हैं। हालांकि उपर्युक्त सरकारी बयान उस समय तक संतोषजनक नहीं हो सकता जब तक किसानों के इस बदले हुए रवैये के पीछे कोई ठोस कारण न दर्शाया जाये। जाहिर है, सरकारी रियायतों के बावजूद किसानों का इस तरह रुख मोड़ना समझ में नहीं आता। मजे की बात यह है कि सरकारी प्रवक्ता हर प्रश्न का बस एक ही नपा-तुला जवाब देते हैं कि व्यापारियों ने अनाज उत्पादन पहले से ही सुरक्षित कर लिया है। किंतु इस सरकारी जवाब को गलत साबित करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बात सिर्फ समझने की है। मामूली समझ रखनेवाला व्यक्ति भी इस गणना को समझ सकता है कि महज एक लाख टन गेहूं सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी को ३५ करोड़ रुपए फंसाने पड़ेंगे। यानी एक वर्ष में ३५ करोड़ रुपए पर न्यूनतम ५ करोड़ रुपए तो उसे ब्याज अदायगी करनी पड़ेगी। ऐसे में कोई भी व्यापारी उस समय तक पैसा नहीं फंसायेगा जब तक उसे यह विश्वास न हो जाये कि बाजार में उसे गेहूं की ऊंची कीमत मिलेगी तथा उसे किसी भी हाल में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। फिर ऐसे वर्ष में जब सरकार 'अच्छी फसल' तथा 'अतिरिक्त अनाज उत्पादन' का ढिंढोरा पीट रही हो, भला कौन व्यापारी इतना मूर्ख होगा कि वह कीमतों का गलत आकलन करके इतनी बड़ी रकम 'अनाज भंडारण' में फंसा दे। यदि इसके बावजूद व्यापारियों ने भंडारण में पैसे फंसाये, तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश के अनाज उत्पादन की असलियत से व्यापारी अच्छी तरह वाकिफ थे तथा सरकार का ढिंढोरा ही गलत था। ऐसे में यह कहना कतई गलत न होगा कि व्यापारी इस सच से वाकिफ थे कि कृषिमंत्री अनाज उत्पादन के जो आंकड़े पेश कर रहे थे, वे पूरी तरह से भ्रामक थे।

यदि उपर्युक्त बात ही सही है, तब तो यह कहना भी गलत न होगा कि राजीव गांधी को आगामी चुनाव में नुकसान पहुंचाने का रास्ता कृषिमंत्री भजनलाल ने ही हमवार किया है। जाहिर है, भजनलाल ने इस तरह के बढ़े-चढ़े आंकड़े सिर्फ इसलिए पेश किये होंगे, ताकि आलाकमान को इस बात का अहसास हो कि भजनलाल कृषि मंत्रालय की बागडोर संभालने में भी काफी निपुण हैं तथा वे देश को भरपूर 'रोटी' उपलब्ध करा सकते हैं। वरना जब अतिरिक्त अनाज उत्पादन हुआ है, तो आखिर वह गया कहां? अनाज की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? अनाज आयात करने की मजबूरी सामने क्यों है? इन

सवालों का जवाब भजनलाल तथा उनके मंत्रालय के सहयोगियों को चुनाव पूर्व अवश्य देना पड़ेगा।

दोष किसका ? : परिस्थितियां जैसी हैं, उन्हें देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार मतदाताओं को उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी। अलबत्ता भजनलाल का 'अतिरिक्त उत्पादन' का नारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए २२ नवंबर के चुनाव में 'जहर' साबित हो सकता है। इस समय राजीव के समक्ष इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वे अधिक-से-अधिक अनाज आयात करके मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगायें। किंतु क्या यह सब कुछ सप्ताह दो सप्ताह में संभव है ?

आखिर अब तक महंगाई को रोकने के लिए सरकार सिवा आयात के और कर ही क्या सकी है? चार लाख टन चावल पहले ही आयात किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर और आयात कर लिया जायेगा। इस आयातित अनाज से जनता को क्या लाभ पहुंचा या पहुंच सकता है, उसे भी जान पाना मुश्किल बात नहीं। शहरी जनता को बस यही सुकून रहा कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज के लिए हाहाकार नहीं मचने पाया।

बिलकुल यही हाल चीनी, दाल तथा तेल के बीजों का है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गन्ने का उत्पादन तो लगभग १० लाख टन बढ़ा, किंतु चीनी का उत्पादन चार लाख टन घट गया। जबकि पिछले साल (८८-८९ के अंत में) लगभग २४ लाख टन चीनी 'बेशी' बतायी गयी थी जिसे ८९-९० के खाते में सुरक्षित रखा गया था। इस तरह से बाजार में (आयात के बगैर) १११ लाख टन से ज्यादा चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी। आंकड़ों के अनुसार सितंबर '८९ के अंत तक मात्र १०२ लाख टन चीनी बाजार में भेजी गयी। यानी भंडारण के अनुसार फिर भी ९ लाख टन से अधिक चीनी उस समय बची होनी चाहिए थी तथा चीनी की किल्लत का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए था। किंतु हुआ पूरी तरह से उलटा। चीनी के आयात पर जोर दिया गया। क्योंकि किल्लत के कारण बाजार में चीनी के दाम आसमान छूने लगे। सवाल यह है कि सितंबर तक तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भंडार में ही चीनी थी फिर कीमतें क्यों बढ़ीं तथा आयात के नारे क्यों लगने लगे ? इस सवाल के जवाब में अधिकारी तथा मंत्री सिर्फ यही कहकर बात आयी-गयी कर देते हैं कि देश में चीनी की किल्लत सिर्फ स्मगलिंग, व्यापारियों द्वारा भंडारण तथा चीनी की अधिक खपत से पैदा हुई है। किंतु सवाल यह है कि संकट के उपर्युक्त कारणों पर पहले से विचार क्यों नहीं किया गया तथा उन्हें मद्देनजर रखते हुए पहले से ही चीनी की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? जब सरकार सारी सचाई से वाकिफ थी, तो उसने चीनी आयात करने का फैसला इतनी देर में क्यों लिया ? मजे की बात तो यह है कि चीनी आयात करने का जो फैसला सरकार ने देर-सबेर लिया भी, वह भी अधूरा था। उल्लेखनीय है कि शुरू में सिर्फ २ से ५ लाख टन के बीच ही चीनी आयात की गयी। जब इस छोटी-सी मात्रा से कुछ बनने-बिगड़ने के आसार नजर नहीं आये, तब हार कर (चुनाव को मद्देनजर रखते हुए) सरकार ने १० लाख टन चीनी आयात करने का फैसला किया। यानी देश को महत्वपूर्ण ५० करोड़ डालर (विदेशी मुद्रा) का नुकसान सहन करना पड़ा।

कुछ अछूता नहीं: कुछ इसी तरह की मिलती-जुलती स्थिति खाद्य तेलों की भी रही। शुरू से ही खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें अपने आप में एक पहेली बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा खपत वाले मूंगफली के तेल की कीमत शुरू के छह माह में ही १८ रुपए प्रति किलो से बढ़कर २५.५० रुपए प्रति किलो हो गयी थी। यही नहीं, इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच प्रति टन मूंगफली की कीमत में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई थी तथा बाद में जुलाई के शुरू की २१,८०० रुपए प्रति टन मूंगफली की कीमत अक्तूबर के शुरू में २६,००० रुपए प्रति टन हो गयी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष मूंगफली उत्पादन में (पिछले साल के मुकाबले) ३७.८ प्रतिशत वृद्धि बतायी गयी है। ऐसे में मूंगफली तथा मूंगफली के तेल की कीमत में वृद्धि समझ में नहीं आती। इसके अलावा हमेशा यह देखा गया कि वनस्पति तथा सरसों के तेलों की कीमतों में मजे का अंतर रहता था। जहां तक वनस्पति उत्पादन की बात है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वनस्पति के उत्पादन में भी १६,००० टन की वृद्धि हुई है, किंतु अक्तूबर के शुरू में भी बाजार में वनस्पति तेल ३० रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था तथा १५ किलो के डब्बे की थोक दर ४३३ रुपए थी। यही हाल देशी घी की कीमतों का है। आमतौर से अच्छा देशी घी प्रति किलो ६५ रुपए से ८५ रुपए के बीच ही मिल पाता है। इस क्रम में सौराष्ट्र घी, जो काफी अच्छा माना जाता है उसका १० किलो का डब्बा ७२०-७९० रुपए में उपलब्ध है। इसी तरह अमूल मक्खन की कीमत भी पहले से बढ़कर प्रति १०० ग्राम ६ रुपए हो गयी है।

अब आइये दालों की कीमत पर एक नजर डाली जाये। दालों की कीमतें तो इतनी ज्यादा बढ़ गयी हैं कि गरीब आदमी के लिए उसका इस्तेमाल मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि अक्तूबर '८८ के मुकाबले आज काबुली चने की कीमत में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह मसूर की दाल पिछले लगभग एक साल में २१ प्रतिशत महंगी हुई तथा अरहर की दाल की कीमत में तो एक मास में ही १६ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।

बिलकुल यही हाल सब्जियों पर आयी महंगाई का है। आलू और प्याज, जिसका इस्तेमाल देश का लगभग हर परिवार किसी-न-किसी रूप में, थोड़ा या ज्यादा करता है, उसकी कीमत भी काफी बढ़ गयी है। स्थिति तो यह है कि कोई भी हरी सब्जी ४ रुपए प्रति किलो से कम में बाजार में उपलब्ध नहीं है। कुछ विशिष्ट सब्जियां जैसे बंदगोभी आदि तो ६ रुपए प्रति किलो से कम में मिलती ही नहीं। अन्य उपभोक्ता वस्तुओं में दूध, चाय की पत्ती, कपड़े (विशेषकर सूती) आदि की कीमतें भी काफी बढ़ी हैं।

कांग्रेस की दुश्मन: ऐसे में यदि कोई यह सवाल करे कि चुनाव के सप्ताह दो सप्ताह पूर्व राजीव सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कर क्या सकती है, तो जवाब दे पाना आसान बात नहीं। आखिर अब तक महंगाई को रोकने के लिए सरकार सिवाय आयात के और कर ही क्या सकी है ? चार लाख टन चावल पहले ही आयात्त किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर और आयात कर लिया जायेगा। इस आयातित अनाज से जनता को क्या लाभ पहुंचा या पहुंच सकता है, उसे भी जान पाना मुश्किल बात नहीं। शहरी जनता को बस यही सुकून रहा कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज के लिए हाहाकार नहीं मचने पाया। किंतु जनता का जो भाग खुले बाजार से अच्छा अनाज खरीदने के पक्ष में रहता है, उसे तो ऐन चुनाव पूर्व भी कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, खरीफ की फसल बाजार में आने तक उसे मौजूदा कीमतों पर ही अनाज खरीदना पड़ेगा।

कुल मिलाकर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि आगामी चुनाव में महंगाई राजीव गांधी तथा उनकी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन होगी, क्योंकि इससे लगभग हर आय वर्ग की जनता प्रभावित है। चूंकि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए उसके समक्ष सिवा धन बल के और कोई रास्ता नहीं है जिसे आधार बनाकर वह चुनाव जीतने का प्रयास करे। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि दौलत के बलबूते ही सरकारें बनती होतीं, तो इस देश में कालेधंधे के सरताज बन गये माफिया डानों ने कब की सरकार बना ली होती।

—कुमारेश चक्रवर्ती

जोड़ों का दर्द ख़ूब ?
आराम दिलाए 'मूव'

30 Gm
moov
moov
moov
moov
moov
Ayurvedic Medicine
(EXTERNAL USE ONLY)

घुटने के जोड़ का दर्द?
पीठ के जोड़ों का दर्द?

उम्र की वृद्धि से या अधिक कठिन परिश्रम करने से आपके शरीर के विभिन्न जोड़, विशिष्ट रूप से आपके घुटने और आपकी पीठ, दर्द के क्षेत्र बन जाते हैं. यह दर्द, जोड़ों के बीच में चिकने तरल की कमी से होता है. जोड़ों में रगड़ होने से आपको पीड़ा और बेचैनी होने लगती है.

जड़ तक पहुँचने वाला

'मूव' में है बहुत गाढ़े प्राकृतिक परिवर्तनशील तेल, जो आपकी त्वचा से होकर जोड़ों में दर्द की जड़ तक पहुँच जाते हैं

जल्द असर करने वाला

'मूव' अपने प्राकृतिक तेलों से -- जो शक्तिदायक लाभकर रस है, तुरन्त ही रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं, चिकना तरल वापस आ जाता है. आपको मिलता है जल्द आराम.

अधिक समय तक आराम दिलाए

'मूव' के मलते ही, उसका बेजोड़ फार्मूला वाला 'बेस' प्राकृतिक तेलों का स्थिर प्रवाह करता है, जो प्रभावित क्षेत्र को अधिक समय के लिए गर्म रखता है, बिना त्वचा को जलन पहुँचाते हुए.
दर्द बिना की गतिशीलता लौट आती है और आप फिर आराम से चल-फिर सकते हैं.

उत्तम निवारक, बेहद असरकारक 'मूव'

जोड़ों का दर्द निवारक

PARAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
Jirendra Chambers, Ashram Road, AHMEDABAD 380 014

राजीव गांधी : देश की एक मात्र आशा

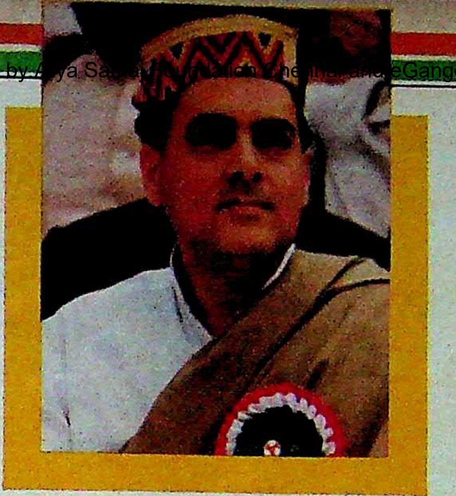

सन १९८४ के जाड़ों की शुरुआत में ही भारत के राजनीतिक क्षितिज पर अंधियारा छा गया। देश खतरे की कगार पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने ही वफादार सुरक्षाकर्मियों की गोली का शिकार बन शहीद हो गयीं। देश में शून्य पैदा हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप का स्थायित्व डगमगाता नजर आया। विद्वेष, विघटन और हत्याओं का दैत्याकार अजगर सामाजिक सद्भाव और मेल-मिलाप को लीलता नजर आया। विनाश के भविष्यवक्ता इससे भी बुरे दिनों के आने की घोषणा करने लगे।

प्रधानमंत्री के एकमात्र जीवित पुत्र उस दिन दिल्ली से दूर कलकत्ता में मौजूद थे। वहीं उनको इस दुर्घटना की खबर लगी और चंद घंटों के भीतर ही उन्होंने अपनी दिवंगत मां की जिम्मेदारियां संभाल लीं। एक कटु तीक्ष्ण यथार्थ उनके सामने आया—एक तरफ देश की जनता दिवंगत नेता के शोक में डूबी आंसू बहा रही थी, दूसरी तरफ कुछ देशवासियों के हाथ अपने ही हमवतन लोगों की गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तब से लेकर दाहसंस्कार तक राजीव गांधी ने जो अपूर्व दृढ़ता दिखाई, जैसी फौलादी खामोशी अख्तियार की, उसी से यह बात साफ हो गयी कि अपने युवा कंधों पर आ पड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने कितनी गंभीरता से संभाला है। अगले तीन दिनों के भीतर उन्होंने आम चुनाव का ऐलान कर यह साबित कर दिया कि उनके यशस्वी नाना, पं० जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता की जो महान परंपरा स्थापित की थी, उसके वास्तविक उत्तराधिकारी वे हैं। यदि श्रीमती गांधी के निधन से एक युग की समाप्ति हो गयी थी, तो उनके बड़े बेटे ने यह यकीन भी दिला दिया था कि राष्ट्र के निर्माताओं ने जिन मानव मूल्यों की स्थापना की थी, उनके प्रति भारत की निष्ठा यथावत् बनी रहेगी।

राजनीतिक स्थिरता

जो ताज पहनता है, कांटों की चुभन भी उसे ही महसूस करनी पड़ती है। पंजाब खौल रहा था, असम और मिजोरम संघर्ष की राह पर थे और गोरखा राष्ट्रीय मोर्चा तैयार हो रहा था। राजीव गांधी के लिए अशांतिग्रस्त देश में शांति स्थापित करना पहली जरूरत थी। कार्य करने की उनकी अपनी शैली थी। हर समस्या को वे सीधे तरीके से हल करना चाहते थे। ईमानदारी से उन्होंने हर समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढ़ने की कोशिश की। संत लोंगोवाल के नेतृत्ववाले अकाली दल से समझौता करने, असम के युवा आंदोलनकारियों से सहानुभूति दिखाने, लालडेंगा से हाथ मिलाने, मिजोरम में सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने और जोशीले घीसिंग को संधिवार्ता के लिए आमंत्रित करने में श्री राजीव गांधी कामयाब रहे। ३ मार्च १९८९ को लोकसभा को संबोधित करते हुए श्री राजीव गांधी ने दावा किया कि "हमने असम, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग क्षेत्रों में शांति और स्थिरता पैदा कर दी है। उत्तर पूर्व में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हमने पूरी तरह खतम कर दी है, लेकिन विद्रोहियों के साथ हमने सख्ती भी बरती है। हमने उनके साथ कोई रियायत नहीं की। हमने उन्हें दिखा दिया है कि सरकार दो शर्तों पर उनसे बातचीत करने को और उनकी बात सुनने को तैयार है—एक तो यह कि उनको हिंसा पूरी तरह त्यागनी होगी, और दूसरे यह कि जो भी बातचीत की जायेगी, वह हमारे संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर की जायेगी।"

सचमुच यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। प्रधानमंत्री ने संत लोंगोवाल से मुलाकात करके एक सार्थक पहल कर दी थी। चंद गुमराह और स्वार्थी लोगों ने चारों

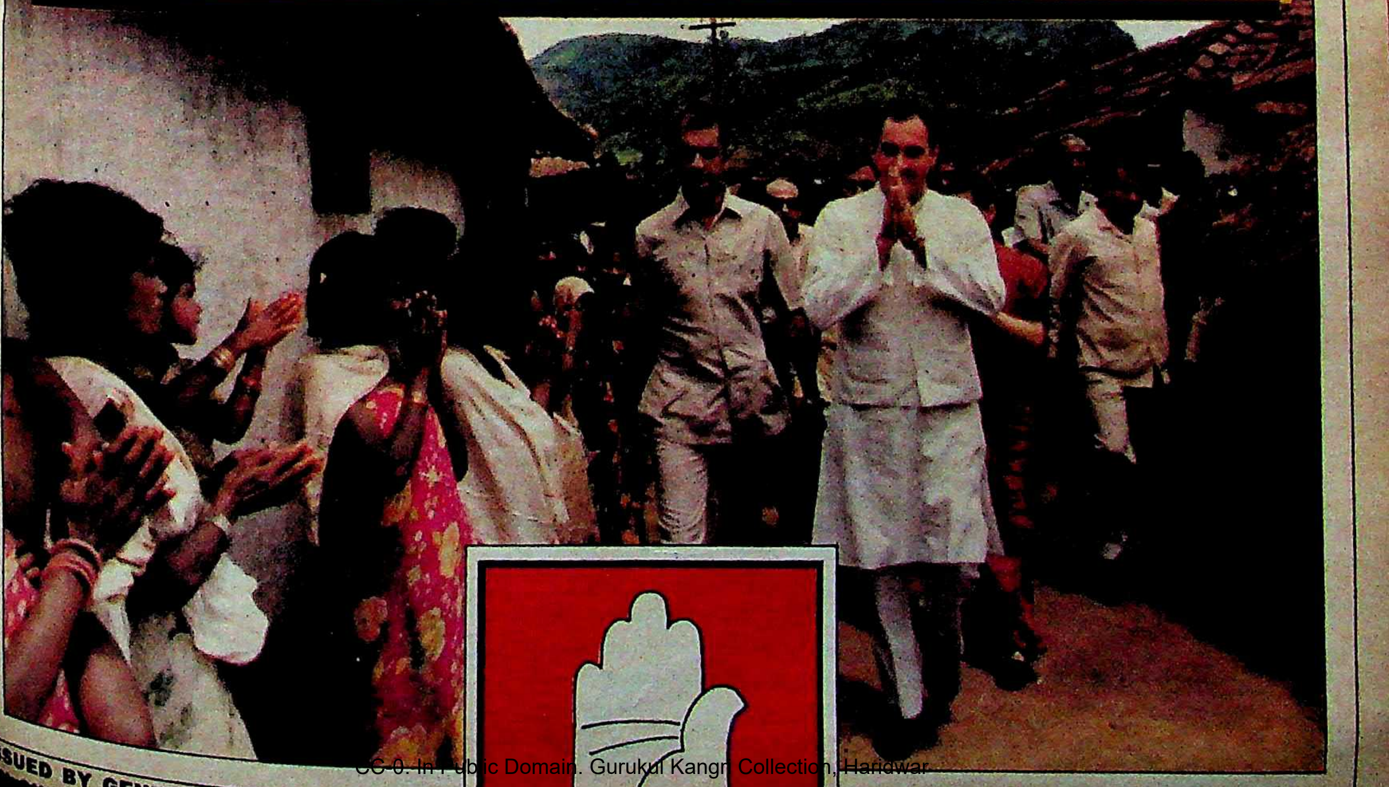

ISSUED BY GENERAL SECRETARY
AICC, 24, AKBAR ROAD,

तरफ आतंक का राज फैला रखा था। पंजाब के हर गांव के लगभग एक तिहाई हिस्से में खून की होली खेली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डर और नफरत से पंजाब के दिल की धड़कन बंद हुई जा रही थी। मेहनतकश पंजाबी आतंकवाद के उलटफेर में अपना दम घुटता महसूस कर रहा था। तभी राजीव गांधी ने कहा, "जैसा कि मैं इस सदन में और इसके बाहर भी कई बार कह चुका हूं, हमने पंजाब-समस्या को सही ढंग से समझने की कोशिश की है। इस समस्या को दो मोर्चों पर सुलझाने की जरूरत है—कट्टरपंथी लोगों की ताकत को खतम करना जरूरी है, आर्थिक और कट्टरपंथी आतंकवादियों का धार्मिक संस्थाओं के भीतर और बाहर स्थित उनके समर्थकों से संपर्क काटना भी उतना ही जरूरी है। दूसरे हमें सख्ती से काम लेना है, ताकि हिंसा और अपराध को एकदम रोका जा सके।"

१९८५ का पंजाब समझौता इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि बातचीत से हर समस्या का हल निकल सकता है। राज्य में चुनाव कराये गये और अकाली दल सत्ता में आ गया। वैसे यह भी विडबना ही रही कि समझौते के समर्थक संत लोंगोवाल भी किसी हत्यारे की गोलियों का शिकार बन गये, पर इसका असर आतंकवादियों पर भी पड़ा। अपने राज्य में अपनी सरकार का मुख-संतोष आतंकवादियों के गले नहीं उतरा। हत्यारों को यह बताना जरूरी हो गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। टेलीविजन पर स्वर्णमंदिर की सफाई का अभियान और इसके साथ ही यह देखकर कि सिख धर्म के तथाकथित अनुयायी इसे किस हाल में छोड़ गये थे, देश की जनता स्तब्ध रह गयी। एक ही झटके से राजीव गांधी ने आतंकवादियों की जड़ें हिला दीं। गलत और विकृत जानकारी फैला-फैलाकर जो जन समर्थन हासिल किया जा रहा था, उसका खात्मा हो गया। फिर पाकिस्तान से एक और समझौता हुआ कि वह राष्ट्रविरोधी ताकतों को कोई समर्थन नहीं देगा। इससे आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत मदद मिली।

राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाने के लिए श्री राजीव गांधी को असुरक्षा में जीनेवाले अपने परिवार को भूल कर २२ घंटे रात-दिन काम में जुटा रहना होता है।

पंजाब पैकेज के साथ-साथ स्थिति सामान्य होने की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गयी। हिंसक वारदातों के जुर्म में पकड़े गये लोगों को छोड़कर जोधपुर में कैद बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। 'विदेशी और उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम' के प्रतिबंध शिथिल कर दिये गये, जगह-जगह शांति समितियां गठित कर दी गयीं और उद्योग तथा कृषि को प्रोत्साहन देने के नये कदमों की घोषणा कर दी गयी। वहां एक ओर आतंकवाद के सफाये का अभियान जारी है, तो दूसरी ओर प्रजातांत्रिक परंपरा को सशक्त करने का प्रयास जारी है। इसी प्रयास के तहत वहां लोकसभा के चुनाव कराये जा रहे हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो लोग सशस्त्र बगावत करने पर आमादा थे, उनको समझा-बुझाकर राह पर लाया गया। चुनाव करा दिये गये और इन क्षेत्रों में शांति स्थापित हो गयी। दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र के लिए स्वशासी पर्वतीय परिषद गठित कर दी जाने से गोरखाओं की युद्धलिप्सा भी समाप्त हो गयी और पृथक राज्य की उनकी मांग समाप्त हो गयी, जिससे पश्चिमी बंगाल का बंटवारा हो जाने की आशंका पैदा हो गयी थी।

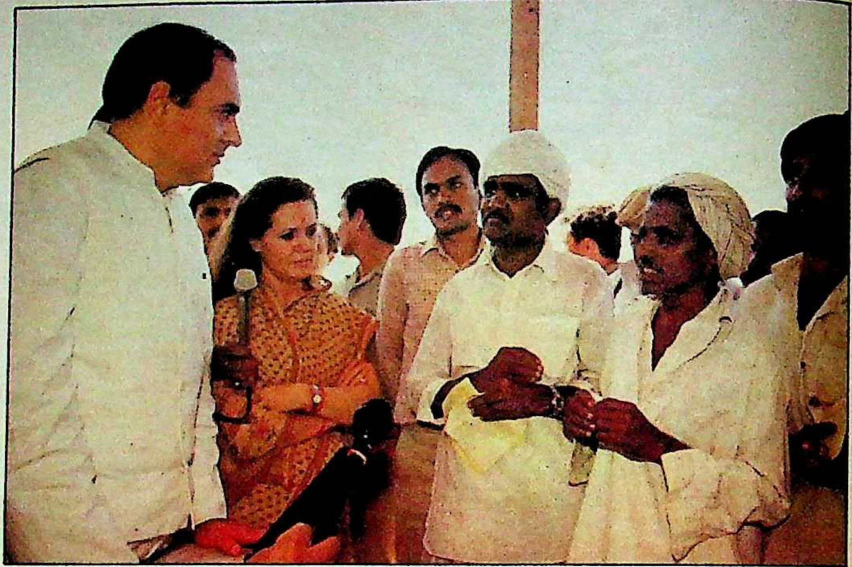

जनता से निकट संपर्क

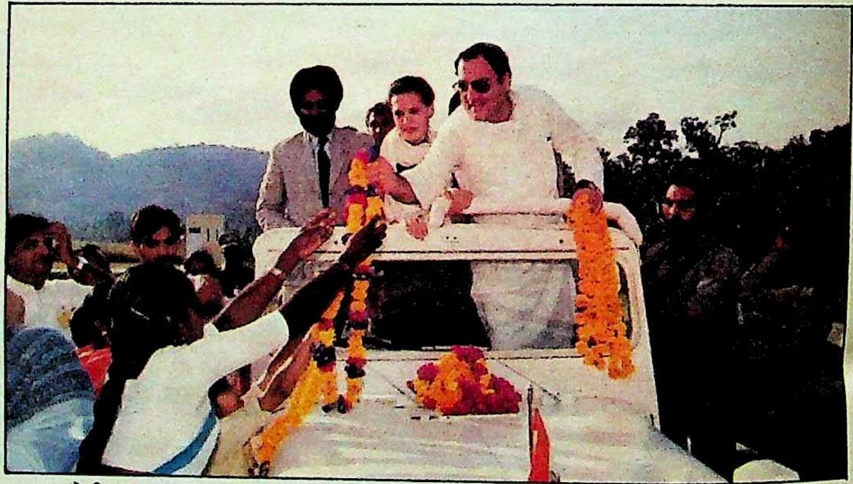

जन-जन को प्रिय

देश में शांति स्थापना के प्रयत्न में सफल होने के बाद श्री गांधी ने देश की आर्थिक संरचना को नया रूप देने की कोशिश प्रारंभ की ताकि देश की सुख-समृद्धि का लाभ समाज के सबसे निचले तबकों तक पहुंच सके। लेकिन इस रास्ते में भी अड़चनें आयीं। देश में इस सदी का भयंकर सूखा पड़ गया और सारी कोशिशों पर पानी फिरता दिखायी पड़ा। इस भीषण संकट का सामना भी उन्होंने सूझ-बूझ से किया और स्थिति को कुछ इस तरह से संभाला कि पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और देश में कोई भूखा न मरे।

अर्थ-व्यवस्था

भारत की राष्ट्रीय उपज का ३० प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि के काम-काज में लगी रहती है, इस तरह खेती भारत का सबसे बड़ा निजी (प्राइवेट) उद्योग है। पंडितजी ने एक बार कहा था कि अगर देश में खाद्य समस्या उठ खड़ी होती है, तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। उनकी बात का गूढ़ अर्थ समझते हुए राजीव गांधी ने लोकसभा में घोषणा की थी—"सैंतीस साल बाद अब वक्त आ गया है, जब हम इस बात को दोहराएं कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को, खेती को, खाद्य और कृषि को दी जानी चाहिए, क्योंकि वही हमारी अर्थ-व्यवस्था की बुनियाद हैं।"

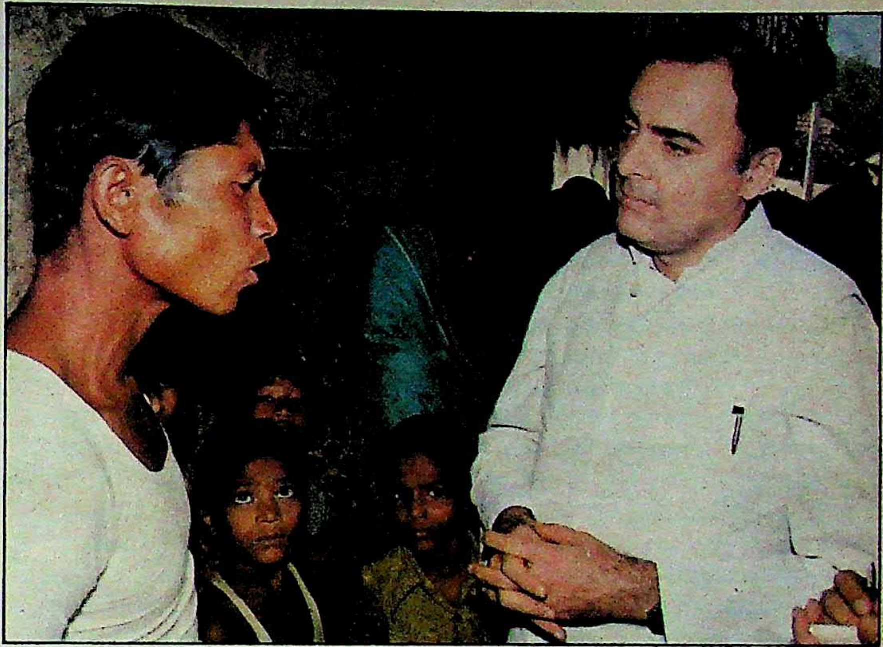

आत्मीय जनसम्पर्क

विगत चार दशकों में भारतीय कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। १९५०-५१ के मुकाबले खाद्यान्नों और तिलहनों की उपज तीन गुना बढ़ गयी है, मछली-उत्पादन चौगुनी और अंडों का उत्पादन नौगुना हो गया है। दुग्ध उत्पादन भी दूने से अधिक हो गया है। चौतरफा वृद्धि के संदर्भ में ही सरकार ने आशावादी रुख अपनाते हुए यह अनुमान लगाया कि इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन १७१० लाख टन से बढ़कर १८२० लाख टन हो जायेगा।

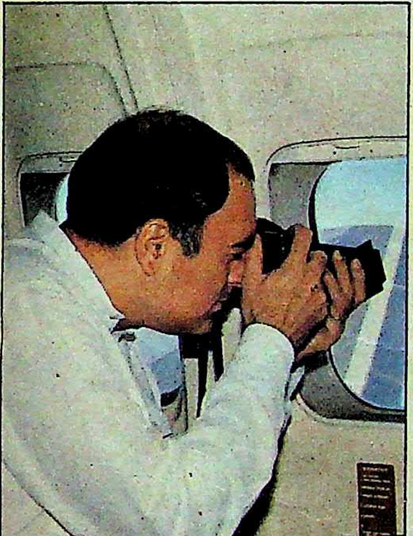

दूरदृष्टि

जहां तक सूखे का सवाल है, राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार ने अभूतपूर्व सूखे का सफलता पूर्वक सामना किया। २.५५ लाख गांवों के साढ़े २८ करोड़ लोगों और १६.८ करोड़ मवेशियों की जान पर बन आयी थी। अगस्त, १९८७ में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने एक कार्ययोजना तैयार कर संकट का सामना करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में १२१६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की। प्रभावित राज्यों में कुएं खोदने की १७ बड़ी ड्रिलिंग मशीनें सक्रिय हो गयीं। ऐसे उपकरणों के लिए विशेष रूप से और धन उपलब्ध कराया गया, जिससे पेयजल की जरूरत को पूरा किया जा सके। पशुओं का चारा पंजाब से ले जाकर राजस्थान और गुजरात पहुंचाया गया तथा साढ़े सात लाख टन अनाज राहत परियोजनाओं में लगे सूखा-प्रभावित लोगों के बीच बांटा गया। इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित १४ राज्यों में सिंचाई योजनाओं के लिए १८८ करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी और १.५१ लाख पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण का विशेष कार्यक्रम चलाया गया। नाबार्ड (एनएबीएआरडी) के जरिए सूखा-प्रभावित किसानों को दूसरी जोत के लिए नये सिरे से आर्थिक सहायता दी गयी और उनके अल्पावधि ऋण को मध्यम अवधि ऋण में परिवर्तित कर दिया गया।

वर्ष १९८७ के अनुभव बड़े कटु रहे, लेकिन श्री गांधी ने उनसे सबक सीखा और कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में उन्होंने कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी। किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्होंने किसानों की प्रशंसा की और कहा, "उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वे देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति हैं। कृषि में आत्मनिर्भरता के कारण ही हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना करने में कामयाब हो सके।"

खेती और किसानों को प्रोत्साहन देने का सिलसिला यहीं खतम नहीं हुआ, बल्कि वार्षिक योजनाओं में इस क्षेत्र के लिए और भी अधिक धनराशि उपलब्ध करायी गयी। छठी पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि-विकास के लिए कुल ३५०० करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की गयी थीं, वहीं अब हर साल कृषि पर ५५०० करोड़ रुपए खर्च किये जाने लगे। उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद खाद के दाम बढ़े नहीं, इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए की पूरक राशि सरकार ने उपलब्ध करायी। इसी का नतीजा है कि खाद के दाम आज भी वही हैं जो १९८१ में थे। पिछले चार सालों में किसानों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा दुगनी कर ११ हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दी गयी, जिससे ७५ प्रतिशत गरीब व सीमांत किसान लाभान्वित हुए। छोटे किसानों के लिए फसल ऋण के ब्याज की दर १८.५ प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर दी गयी। सूखे की मार से राहत पहुंचाने के लिए फसल बीमे की योजना लागू की गयी।

राजीव शासन ने किसानों के हित में और भी बहुत से कार्य किये। वसूली मूल्य के निर्धारण के तरीकों को स्थिरता प्रदान की गयी और कृषि उत्पादन के व्यापार की शर्तों को अन्य व्यवसायों के मुकाबले पुनरीक्षित किया गया। श्री गांधी ने घोषणा की, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम सुनिश्चित करेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए व्यापार की शर्तें किसानों के हित में निर्धारित हों। वसूली केंद्रों का विस्तार हुआ। अच्छी सड़कों और गांव-गांव में स्थापित शीत गृहों के जरिए श्री गांधी ने कृषि उत्पादनों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। किसानों के लिए ऋण सुविधा का व्यापक विस्तार किया गया तथा इस दिशा में चार महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। सौ करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा सहकारिता क्षेत्र खासकर अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों को दी गयी, फसल के लिए दिये जानेवाले अल्पावधि ऋण के वार्षिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गयी, वर्षा पर आश्रित किसानों को विशेष ऋण सुविधा दी गयी तथा ऋण एव आर्थिक सहायता को सहज बनाने के लिए कृषि ऋण कार्ड जारी किये गये। पहली बार फसल को होनेवाली क्षति से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विस्तृत राहत नीति लागू की गयी। सिंचाई के लिए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण करके उन्हें कारगर ढंग से लागू करने की व्यवस्था की।

जनता को सत्ता देने के लिए श्री राजीव गांधी पंचायत और नगरपालिका बिल लाये, लेकिन विपक्ष ने इन्हें राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया।

भोजन एवं आवास

भारत को विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जरूरी था कि देश की जनता के लिए जरूरत की चीजों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए १९८८ के सूखे के दौरान वितरण केंद्रों को अत्यधिक सक्रिय बनाये रखा गया तथा १८३.१ लाख टन खाद्यान्नों में से १६९.९ लाख टन अनाज उचित मूल्य की

दुकानों से जनता तक पहुंचाया गया। यही नहीं, १.८९ लाख टन गेहूं तथा ०.५६ लाख टन चावल उन राज्यों के लिए आवंटित किया गया जो सूखाग्रस्त घोषित हुए थे। इसके अलावा १० लाख टन अनाज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखा गया। यही नहीं, १.०५ लाख टन गेहूं पोषण कार्यक्रमों के लिए भी अलग रखा गया। अनाज को देश के दूरदराज इलाकों में पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंपी गयी। निगम ने सभी संभव प्रयास करके दूरदराज इलाकों में अनाज के अभाव को समय पर समाप्त किया। अपनी इस जिम्मेदारी को सरंजाम देने के लिए निगम ने १९० ८८ लाख टन अनाज सड़क, रेल तथा जल परिवहन के जरिये विभिन्न स्थानों तक पहुचाया। यही नहीं, सूखाग्रस्त राज्यों के किसानों की सहायतार्थ सरकार ने अनाज वसूली की शर्तों में भी ढील दी तथा वसूली की प्रक्रिया को तेज करके जनवरी '८९ तक ५३.३ लाख टन अनाज अपने नियंत्रण में कर लिया।

खाद्य संरक्षण: इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी था कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकताएं नजरअंदाज न हों। नतीजतन इस काम के लिए खाद्य मंत्रालय बनाया गया, जिसका काम केवल कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मात्र देना नहीं था, बल्कि कृषि उत्पादों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना भी था। इस मंत्रालय के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद पाउडर वाले दूध, बच्चों के दूध, फल तथा वनस्पति उत्पादों के निर्यात तथा मुर्गी पालन उद्योग में अभूतपूर्व प्रगति देखी गयी। १९८८ के आंकड़ों के अनुसार ४९,३८९ टन फल तथा वनस्पति (सब्जियां) निर्यात की गयीं तथा एक लाख टन दूध का उत्पादन हुआ। इसके अलावा मंत्रालय को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वह कृषि आधारित उद्योग में नयी टेक्नालाजी के प्रवेश का मार्ग सुलभ बनाये। इसी के साथ अनाज दलने तथा अनाज के उत्पाद तैयार करने वाली मिलों को नयी तकनीकी से लैस भी किया गया। १९७० में स्थिति यह थी कि देश में चावल मिलों की संख्या नगण्य थीं, किंतु आज देशभर में २४,५०० चावल मिलें अस्तित्व में हैं, जहां बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। यही नहीं, तंजावुर स्थित चावल शोध केंद्र तथा खड़गपुर स्थित पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी सेंटर को सहायतार्थ बड़ी मात्रा में अनुदान दिया गया, ताकि बेहतर से बेहतर बीजों तथा उम्दा किस्म की मिट्टी को सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ वातानुकूलित भंडारों पर भी व्यय बढ़ाया गया तथा ऐसी नीतियों को भी मजबूत बनाया गया, जिससे विदेशी तथा भारतीय जहाजों का विभिन्न बंदरगाहों तक पहुंचाना संभव हो पाये, ताकि भारतीय कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक निर्यात हो सके।

पंजाब, असम, मिजोरम और दार्जिलिंग में अराजकता पर अंकुश लगाने के लिए श्री गांधी ने टकराव के बजाय समझौतों की आधारशिला रखी।

आवास: राष्ट्रीय आवास योजना के तहत सरकार ने पहली बार देश के हर परिवार को आवास देने का संकल्प किया है। इस योजना के तहत अब तक ३५ लाख भूमिहीन परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए भूमि पा चुके हैं तथा १६ लाख परिवारों को निर्माण हेतु सहायता दी गयी है। इसी तरह स्लम डिवेलपमेंट स्कीम के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अतिरिक्त १०० करोड़ रुपए स्वीकृत करने से लगभग ७६ लाख स्लम निवासियों को और राहत मिली है तथा उनके रहन-सहन में तब्दीली लाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह बड़े शहरों में झोपड़पट्टियों में रहनेवाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम भी सरकार ने शुरू किया है। यही नहीं, अकेले गुजर-बसर करने वाली महिलाओं तथा विधवाओं की आवासीय समस्या हल करने के लिए भी सरकार ने कार्यक्रम शुरू किये हैं। देश के नागरिकों की आवासीय समस्या हल करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ३८ निर्माण केंद्र खोले गये हैं, जिनका काम भवनों के निर्माण के लिए उचित दाम पर उचित सामान उपलब्ध कराना तथा बेरोजगार युवकों, छोटे ठेकेदारों तथा दस्तकारों को आवश्यक प्रशिक्षण देना है।

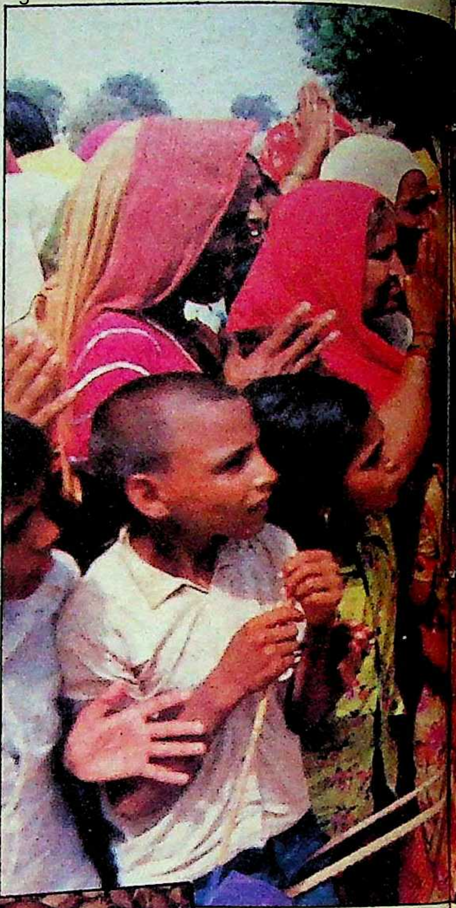

कल्याण

संविधान निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया। इसको ध्यान में रखते हुए श्री राजीव गांधी ने ऐसी योजनाओं की नींव डाली है, जिनसे बहुसंख्यक मेहनतकश आम जनता की हालत में लगातार बेहतरी हुई है। १९७० से श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र को अशक्त बनानेवाली कमरतोड़ महंगाई को हमेशा-हमेशा के वास्ते खतम करने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किये गये। इन कार्यक्रमों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना, आत्म निर्भर बनाने के लिए युवकों का प्रशिक्षण, पर्वतीय, सूखाबहुल और ऊसर क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी शामिल है। इन कामों पर ७२४३.३७९ करोड़ रुपए लगाय गये हैं। उम्मीद है कि १९८९ के अंत तक देश में महज छब्बीस प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह जायेंगे, १९८४ में

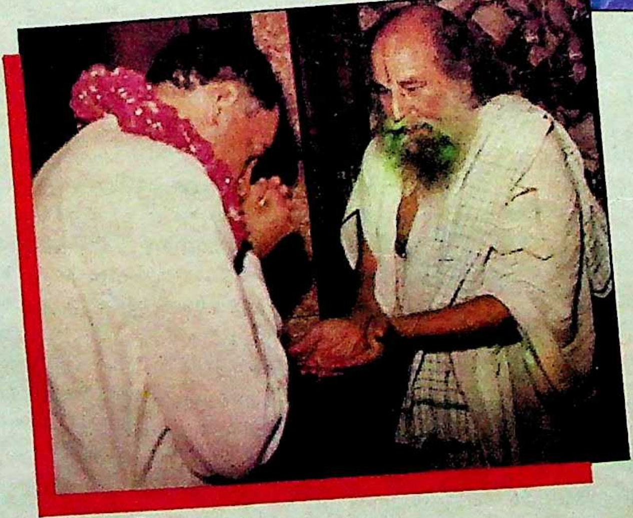

विरासत के प्रति आदर

महिला कल्याण को सर्वोपरि महत्व

इनकी संख्या आबादी का सैंतीस प्रतिशत थी। देश में ४.४ करोड़ निर्धन ग्रामीण परिवार हैं। ग्रामीण जवाहर रोजगार योजना इन सभी परिवारों के कम-से-कम एक सदस्य को सौ दिन रोजगार देने के लिए बनी है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग

देश के ज्यादातर गरीब लोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों का कुछ हिस्सा और कमजोर वर्ग की जनता आती है। इसलिए गरीबी मिटाने के किसी भी कार्यक्रम में इन पर ध्यान देना जरूरी था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित प्रयास किये गये। इस दिशा में प्रथम सशक्त कदम प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उठाया। उन्होंने १९९० में समाप्त हो रही इन वर्गों के आरक्षण की सीमा को १० वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम की स्थापना की गयी। जिसका काम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वित्तीय संस्थाओं के जरिए संसाधन जुटाना है। गंदगी को सिर पर ढोने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था की गयी और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम बनाये गये। यह भी निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई भी पद आरक्षणमुक्त न रहे और इस वर्ग के लिए नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया गया। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर्याप्त चुस्त-चौकस बनायी गयी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए सिंचाई हेतु दस लाख कुंओं की महती योजना शुरू की गयी। इंदिरा आवास योजना के शुभारंभ से हर आदिवासी के लिए मकान का सपना पूरा होने लगा। अब तक ४.३ लाख घर उन्हें दिये जा चुके हैं। इन्हें बिजली सुलभ कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना लागू हुई। सौ करोड़ की शुरुआती पूंजी से भारतीय जीवन बीमा निगम ने कमजोर वर्गों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की। अपना मकान प्राप्त करने की दो योजनाओं के अंतर्गत दो लाख बुनकर परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी के पंद्रह सूत्री कार्यक्रम को नया संबल प्रदान करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पुलिस बल में नौकरियां देने के लिए खास व्यवस्था की गयी। प्रतियोगिता-परीक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को आगे लाने और सफल बनाने के लिए उनकी संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं शुरू की गयीं।

स्वास्थ्य

पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की वजह से भारत के नागरिक की औसत आयु अब अट्ठावन वर्ष पहुंच गयी है, जबकि १९४७ में औसत आयु महज बत्तीस वर्ष थी। माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए खासतौर पर जोर दिया गया। कोशिशें रंग लायीं। देश के हर कोने तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गयीं। समन्वित बाल विकास सेवाओं को विस्तार दिया गया। नतीजा यह हुआ कि देश के २२०० ब्लाकों में रहनेवाले १.२ करोड़ बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलानेवाली माताओं को समुचित आहार मिलने लगा। तीन लाख से ज्यादा औरतों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्ति दी गयी। तपेदिक खतम करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं संचालित की गयीं। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में खाने के नमक के रूप में आयोडीनयुक्त नमक सुलभ कराने की महती योजना है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण सेवाओं के अंतर्गत भारी संख्या में औरतें और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चों और उनकी माताओं को कुपोषणजन्य रक्तअल्पता, विटामिन ए की कमी से होनेवाले अंधेपन तथा बैक्टीरिया के संक्रमण से होनेवाले घातक निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) को कम-से-कम करने की ओर स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर ध्यान है।

महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के नक्शेकदम पर स्त्रियों के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तावित की है। उन्होंने स्त्रियों को समानता तथा सामाजिक न्याय दिलाने के अलावा उन्हें राष्ट्रीय अर्थतंत्र की मुख्यधारा में शामिल करने के तौर-तरीकों के लिए समग्र रूप से पुनर्विचार का आह्वान किया है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में महिला विकास निगम स्थापित किये गये हैं। इन निगमों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ कराना है। ३०६३८ कामकाजी औरतों के लिए अब तक ४७९ हास्टल स्थापित किये गये हैं। माताओं के कामकाज के दौरान दिन में उनके नौनिहालों की देखरेख के लिए ३८२३ केंद्र भी अब तक खुल चुके हैं। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत १०७३०० औरतों को रोजगार देने के लिए ८४४७ इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के तत्वावधान में जरूरतमंद स्त्रियों को रोजगार दिया जाता है।

श्री राजीव गांधी ने मालदीव में तत्काल सेना भेजकर वहां की सरकार की रक्षा की और भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाया।

पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "असली स्वराज चंद लोगों के सत्ता हथिया लेने से नहीं, बल्कि सभी लोगों के क्षमता प्राप्त करने से आयेगा।" इस वक्तव्य को जीवंत वास्तविकता प्रदान करने का सपना भारत देश ने देखा था तथा पिछले चार दशकों में इस दिशा में कदम उठाये गये। १५ मई, १९८९ इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन था। करोड़ों लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को गतिशील बनाते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने निश्चय किया कि भारत मे हर व्यक्ति को अपनी तकदीर का फैसला करने का अधिकार हो और इसी दिन पंचायती राज से सम्बद्ध चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। देश की चार दशकों की समग्र स्थिति का लेखा-जोखा करते हुए तीन माह बाद शहरी निकायों में जनतांत्रिक प्रक्रिया का संचार करने के लिए इसी तरह का पैंसठवां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री ने पेश किया।

श्री राजीव गांधी ने महसूस किया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे बुनियादी संगठनों में अंतर्निहित खामियों के कारण ये संस्थाएं निर्जीव हो कर रह गयी हैं। इन संस्थाओं के निलंबन और बर्खास्तगी के अंतहीन सिलसिले की वजह से पचायतें महज कागजी शेर रह गयी हैं। प्रधानमंत्री गांधी के अनुसार पंचायतों को भी विधानसभाओं जैसा महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर पंचायतों का मखौल नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की जड़ों को नीचे तक पहुंचाने, विकास में गांव के लोगों को शामिल करने और सत्ता के दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायतों को नया स्वरूप बख्शना श्री राजीव गांधी ने आवश्यक समझा।

राष्ट्रीय गौरव और एकता के लिए कटिबद्ध श्री राजीव गांधी राजघाट और श्रीलंका में दो प्राणघातक हमलों से बाल-बाल बचे हैं।

मतदाताओं एवं क्षेत्र विशेष की जरूरतों को मद्देनजर रखकर पंचायतों को अपनी योजनाएं बनाने का अधिकार देने का प्रावधान रखा गया। पंचायती राज विधेयक में महिलाओं को प्रतिनिधित्व आरक्षित है। महिलाओं की भागीदारी जरूरी बनाये जाने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो पूरी आबादी का आधा हिस्सा औरतों का है। घर की सुचारु रूप से वित्तीय व्यवस्था का भार स्त्रियों पर ही रहता है। तीसरे महिलाएं ही हमारी प्राचीन परंपराओं की संरक्षक हैं।

कमजोर वर्गों के लिए पंचायत राज विधेयक में जवाहरलाल नेहरू के उस मंतव्य की अनुगूंज प्रतिध्वनित होती है, जिसे उन्होंने तीस वर्ष पूर्व १९५९ में गांधी जयंती के अवसर पर नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज का शुभारंभ करते

ऐतिहासिक पहल : चीन में देंग के साथ

जनता के रूबरू

हुए प्रस्तुत किया था : "लाखों गांवों की तरक्की आसान काम नहीं है... हमारी कामयाबी की रफ्तार धीमी होने की वजह यह है कि हम सरकारी मशीनरी पर निर्भर हैं। एक अफसर शायद इसलिए जरूरी है, चूंकि वह माहिर होता है। मगर इस काम में तभी तेजी आ सकती है, अगर आम लोग अपने हाथों में जिम्मेदारी ले लें। आम लोगों के साथ महज सलाह-मशविरा ही न किया जाये, उन्हें असरदार ताकत भी सौंपी जानी चाहिए।"

नगरपालिका विधेयक पंचायती राज विधेयक का पूरक है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महसूस किया कि जनतंत्र को आधारभूत स्तर—गांव स्तर—तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह इसे शहरी निकायों में भी पहुंचना चाहिए। इस संदर्भ में स्थानीय निकायों की केन्द्रीय परिषद और अखिल भारतीय नगर प्रमुख परिषद के संयुक्त प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राजीव गांधी ने जिलों के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से भारी पैमाने पर सलाह मशविरा किया तथा तय किया कि पंचायतों की ही तरह नगरपालिकाओं के भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवैधानिक रक्षाकवच सुलभ होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इन दोनों विधेयकों के लोकसभा में भारी बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में कुछ विपक्षी दलों ने इसे पारित नहीं होने दिया। इससे प्रजातंत्र का प्रसार अवरुद्ध हुआ है और आम आदमी को मिलने वाली सत्ता को बीच में रोक दिया गया है। लेकिन श्री राजीव गांधी इन विधेयकों को पारित करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और यह शेष कार्य वे इन चुनावों के बाद निश्चित रूप से संपन्न करेंगे।

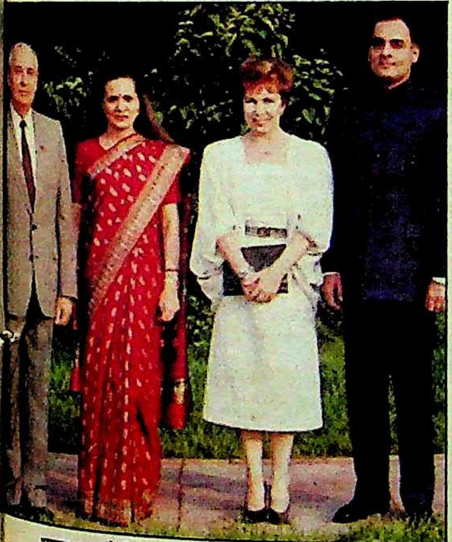

भारत-रूस मैत्री को नये आयाम : गोर्बाचेव के साथ श्री गांधी

विदेशनीति

दिल्ली घोषणापत्र में जब भारत के साथ-साथ सोवियत संघ ने भी इस बात का समर्थन किया कि अणुशस्त्रों की समाप्ति से ही धरती पर शांति स्थापित रह सकती है, तब एक महत्वपूर्ण पहल हुई। बेलग्रेड से लेकर क्वालालम्पुर में हुई राष्ट्र मंडल देशों के शासन-प्रमुखों की बैठक तक में जब श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण की रक्षा के लिए 'पृथ्वी रक्षा कोष' को मान्यता मिल गयी, तो देश के गौरव में चार चांद लग गये। भारत ने अडोस-पड़ोस के राष्ट्रों के प्रति जो नीति अपनायी, उसकी सराहना दोनों महाशक्तियों ने की। पिछले वर्ष के दिसंबर माह में जब मिखाइल गोर्बाचेव भारत आये, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विश्व के इस भूभाग में भारत की नीति-कुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

जब श्री गांधी ने श्रीलंका में राहत सामग्री हवाई मार्ग से भिजवाने का निश्चय किया, तब भी अनेक अदूरदर्शी लोगों ने इसे श्रीलंका के घरेलू मामले में हस्तक्षेप बताया था। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गयी थी और भारत कें हस्तक्षेप के बाद ही वहां शांति और स्थायित्व की स्थापना हो पायी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने की सहमति से भारत को एक बार फिर हिंसा और ध्वंस का तांडव रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। शोर भी मचा कि हमारी सीमा पर एक और लेबनान बन रहा है, परंतु लोग यह नहीं समझ पाये कि अमन और शांति के लिए प्रतिबद्ध भारत के सामने इसके सिवा दूसरा चारा नहीं था। लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि श्री गांधी का दृष्टिकोण ही सही था। वे शुरू से कहते आ रहे थे कि जैसे ही श्रीलंका में शांति स्थापना हो जायेगी, भारतीय सेना वापस लौट आयेगी। भारतीय प्रयासों से ही उत्तरी और पूर्वी लंका के स्वशासी राज्य में निर्वाचित सरकार की स्थापना हो पायी। इसके बाद भारतीय सेना वापस लौटने लगी। जैसी कि स्थिति विद्यमान थी, उसमें किसी शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्र की सेना हरगिज वापस न लौटती, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात से कितनी भी निराशा होती। श्री गांधी ने अपनी प्रतिबद्धता को अक्षरशः निभाया। शांति स्थापित होते ही भारतीय सेना वापस लौट आयी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शांति स्थापना के इस प्रयास में लंका में ही श्री गांधी पर घातक हमला भी हुआ था, जो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता था।

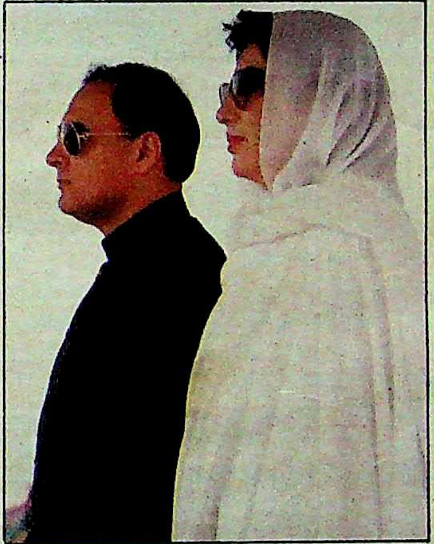

शिमला भावना को पुनर्जीवन : बेनजीर भुट्टो के साथ

इसके बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति ने तात्कालिक मदद मांगी, क्योंकि कुछ भाड़े के सैनिकों ने इस छोटे से राष्ट्र कें अस्तित्व को ही संकट में डाल रखा था। सार्क सम्मेलन में भारत ने यह दावा दोहराया था कि संकट की स्थिति में दोनों देश एक-दूसरे की मदद करेंगे। चंद घंटों के अंदर ही भारत ने मालदीव में होनेवाले विद्रोह को कुचल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल वह चंद घंटों के अंदर ही करके किसी भी दुश्मन से निपट सकता है। सारी दुनिया को मानना पड़ा कि एशिया में भारत का अभ्युदय एक नयी शक्ति के रूप में हो रहा है।

सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता मिखाइल गोर्बाचेव के दिल्ली आने के बाद भारत-सोवियत मैत्री एक सशक्त साझीदारी में बदल गयी। इसके कुछ ही पहले संयुक्त राष्ट्र संघ अमरीका के रक्षा सचिव कैस्पर वैनबर्गर ने नयी दिल्ली में कुछ दूसरी तरह की बातचीत की थी और उन्होंने पाकिस्तान के नये सिरे से शस्त्रास्त्रों की पूर्ति की घोषणा की थी। यह साफ तौर पर भारत से विश्वासघात था। इसके बाद ही श्री गोर्बाचेव ने भारत के साथ भागीदारी के सभी द्वार खोल दिये। भारत की ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए २००० करोड़ रुपए तक सहायता देने की बात उन्होंने की और इसके साथ ही अत्यन्त परिष्कृत किस्म के सर्वोत्तम रूसी अस्त्र-शस्त्र भारत को उपलब्ध कराने का वचन दिया। उसी समय यह बात विश्व के दूसरे राष्ट्रों की समझ में आ गयी कि रूसी किसी कमजोर राष्ट्र की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र के एक सशक्त स्वतंत्र राष्ट्र को सहयोग दे रहे हैं जो शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हुए भी अपनी ताकत की एक अलग पहचान बनाये हुए है। श्री गोर्बाचेव के भारत दौरे के बाद ही राजीव गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि भारत को कमजोर समझना किसी भी राष्ट्र को महंगा पड़ेगा।

इस सदी के सबसे भयंकर सूखे ने देश को अपनी चपेट में लिया, लेकिन श्री गांधी ने किसी को भी भूखों नहीं मरने दिया।

सोवियत रूस ने आपसी संबंधों में जो प्रगाढ़ता दर्शायी थी, वह दरअसल श्री गांधी की व्यक्तिगत राजनीतिक सफलता थी। किसी राजनयिक ने इस पर टिप्पणी भी की थी, "संपूर्ण विश्व की राजधानियों में इसका गंभीर प्रभाव होगा।" श्रीमती गांधी की श्री ब्रेझनेव से व्यक्तिगत घनिष्ठता थी, श्री नेहरू की खुश्चेव से मित्रता विश्वविख्यात है। श्री राजीव गांधी की स्थिति इससे बिलकुल भिन्न थी। उनको शुरुआत से ही पाश्चात्य देशों का समर्थक माना जाता था। लेकिन श्री गोर्बाचेव के इस दौरे के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयी और भारत तथा रूस एक दूसरे के बहुत निकट आ गये।

"एक ऐसा दिन आयेगा जब मनुष्य अपनी खोयी हुई विरासत को वापस पाने के लिए अपने विजय-पथ पर आगे बढ़ेगा।... लोगों में एकता और सद्भाव लाना ही सभ्यता का तकाजा है।" श्री गांधी, बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन

में भारतीय कवि रवींद्रनाथ ठाकुर के उद्धरण पेश कर रहे थे। यह शांति और सद्भाव की एक विजय ही है कि हम मनुष्यता की खुशहाली की खातिर बातचीत और विचार-विमर्श के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। इस तरह, जब श्री गांधी बहुसंख्यक देशों को १९६१ की बेलग्रेड घोषणा के महत्व की याद दिला रहे थे, तब वे न केवल अपने नाना और चार अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा चलायी गयी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, बल्कि प्रभुत्व की घिसी-पिटी मानसिकता से आगे कदम बढ़ा रहे थे और एक ऐसे विश्व का रास्ता भी दिखा रहे थे जो टकराव और दुर्भावना से मुक्त हो। भारत लगातार एक नई विश्व व्यवस्था की मांग करता रहा है और यह प्रधानमंत्री की पहल की ही देन है कि नाभिकीय हथियारो की पूर्ण समाप्ति की मांग उठानेवाली दिल्ली घोषणा तनाव में कमी के नये दौर में पहुंच गयी। अगर नेहरू ने विश्व-सहमति की नींव डाली, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने परस्पर विरोधी महाशक्तियों को समान दूरी की नीति को हकीकत में तब्दील किया, तो तीसरे व्यक्ति राजीव गांधी ही हैं, जिन्होंने इस प्रकार आगे कदम बढ़ाया कि शांति का लक्ष्य सिद्ध हो सके।

कांग्रेस-इ भानुमति का कुनबा नहीं, वह एक ऐतिहासिक पार्टी है, जिसके एकमात्र नेता श्री राजीव गांधी हैं और वही देश को स्थिरता दे सकती है।

जहां तक पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाने की बात है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी और चीन में बदलते राजनीतिक समीकरण का भरपूर फायदा उठाने से चूके नहीं। पाकिस्तान में जिया शासन के अंत तथा बेनजीर भुट्टो के हाथ में सत्ता आते ही राजीव गांधी ने समय रहते शिमला समझौते का पुनरावलोकन करना ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने पूरी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ ऐसा समझौता किया, जिससे दोनों देशों में आतंकवाद पर रोक लग सके, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब तक पाकिस्तानी सहायता-सहयोग पर रोक नहीं लगती, पंजाब में दिनोंदिन पनप रहे आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। साथ ही, पाकिस्तान के साथ हुए समझौते से सियाचिन पर जारी युद्ध को शांत करने में भी सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी २०० दिनों के अंदर दो बार पाकिस्तान गये। आतंकवाद तथा सियाचिन मसले को शांत करने के उद्देश्य के साथ उनकी यात्राओं का लक्ष्य यह भी था कि दोनों देशों की जनता के बीच साम्राज्यवादियों द्वारा खड़ी की गयी नफरत की दीवार को ढहाया जा सके।

इसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत-चीन के बीच २६ वर्षों से बिगड़े संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से बीजिंग रवाना हुए, क्योंकि दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद भारत के लिए स्थायी सिरदर्द बन चुका था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा से पूर्व सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आठ दफा वार्ताएं विफल हो चुकी थीं। किंतु राजीव गांधी के बीजिंग दौरे के दौरान चीन के वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता दंग झियाओ पंग ऐसे प्रभावित हुए कि वे यह कह बैठे कि 'जो गुजर गया, उसे भूल जाना ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि विश्व की दो बड़ी सभ्यताएं (चीन और भारत) अपनी पुरानी गलतियों से सबक क्यों नहीं हासिल करतीं।' दंग झियाओ पंग की बातें इस बात का स्पष्ट संकेत थीं, कि चीन भी भारत से संबंध सामान्य बनाने को उत्सुक है तथा वह पिछली बातें भुलाकर नये सिरे से रिश्ते बनाने का अभिलाषी है। इसी यात्रा के दौरान चीन ने यह भी वायदा किया था कि वह भविष्य में किसी भारत विरोधी तत्व को हथियार या प्रशिक्षण नहीं देगा, ताकि उत्तर पूर्व में भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लग सके। इसके अलावा इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत-चीन सीमा की देखरेख पर चीन कम-से-कम धन व्यय करेगा। भारत भी इस बात पर सहमत हुआ। इसी के साथ व्यापार तथा संस्कृति से संबद्ध समझौते भी हुए, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देश १९६२ के पूर्व 'हिंदी-चीनी' भाई-भाई के माहौल को पुनः जीवन देने के लिए तैयार हैं। चीन से दुश्मनी खतम होने का संकेत तो दंग झियाओ पंग ने अपनी राजीव गांधी से ९० मिनट की भेंट के अंतिम क्षणों में यह कहते हुए दिया था, "आप जवान हैं तथा आप ही भविष्य हैं। हमारा क्या ? हम तो इतिहास में गुम हो जाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। दुनिया में राजनीतिकों की जो नयी पीढ़ी तैयार हुई है, उसका लक्ष्य सभी तरह के विवादों को समाप्त करके शांति और सौहार्द्र के माहौल को मजबूत बनाना है। आप उसी नयी नस्ल के एक सदस्य हैं। अब यह आपके हाथों में है कि आप विश्व-व्यवस्था को क्या रूप देते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि आपको जो अवसर मिला है, उसका होशियारी से इस्तेमाल करिये।"

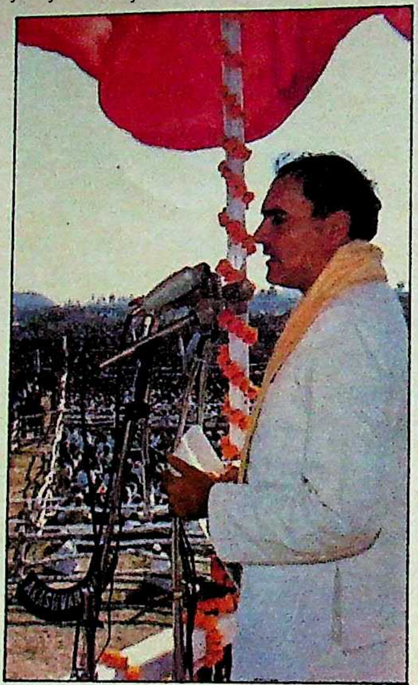
अभूतपूर्व लोकाकर्षण

इस तरह से प्रधानमंत्री अपने शांति एवं सद्भाव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठिन मौकों पर हिम्मत नहीं हारे, किंतु विडंबना यह रही कि उन्हें अपने ही देशवासियों के कटाक्ष सहने पड़े। फिर भी प्रधानमंत्री घबराये नहीं। नेहरू परिवार के एक बहादुर सदस्य की हैसियत से राजीव गांधी देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की योजनाएं बनाते तथा क्रियान्वित करते रहे। उनका प्रयास विफल नहीं हुआ। उनकी मेहनत रंग लायी तथा विश्व मानचित्र पर भारत का मुखौटा और उज्ज्वल हुआ। आज २०वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में भारत द्वारा अग्नि तथा पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रयोग इस बात का सबूत है कि राजीव काल में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वह भी ऐसे माहौल में, जब देश की सांप्रदायिक विघटनकारी शक्तियां चारों ओर से देश को खोखला करने के प्रयास में जुटी हैं। देश को यहां तक पहुंचाने में राजीव गांधी ने थोड़ा बहुत त्याग नहीं किया है। प्रतिदिन २०-२२ घंटे काम करना, परिवार की परवाह न करना, हर समय अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना, राजीव गांधी को अपने नाना और अपनी मां से विरासत में मिला है। यही नहीं, राजीव की उम्र का तकाजा तो यह था कि मनमाफिक शासन करते तथा नामवर तानाशाह बन जाते, किंतु उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को फूलने-फलने का मौका दिया। उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने चुनाव की घोषणा की है। हालांकि देश में सांप्रदायिकता ने जैसा माहौल बना रखा है, उस मौके पर चुनाव की घोषणा संभव न थी। फिर भी, उन्होंने जनता के निर्णय को सम्मान देने के लिए चुनाव की घोषणा की है। १८ वर्ष के युवकों को मताधिकार दे कर उन्होंने प्रजातंत्र की रगों में नये खून का संचार किया है। एक बार फिर राजीव गांधी देश में राजनीतिक स्थिरता, देश की अखंडता और विकास की निरंतरता को बनाये रखने के लिए जनसेवा प्राप्त करने के वास्ते महान देश की महान जनता के सामने हैं। विघटनवादी और सांप्रदायिक ताकतों के खतरों से देश को सुरक्षित रखने के लिए श्री राजीव गांधी देश की एकमात्र आशा है। ■

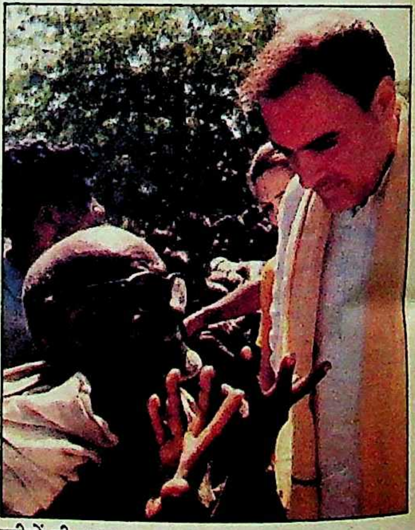
गरीबों की आशा

लोकसभा व विधानसभा चुनाव

माहौल १९६७ जैसा

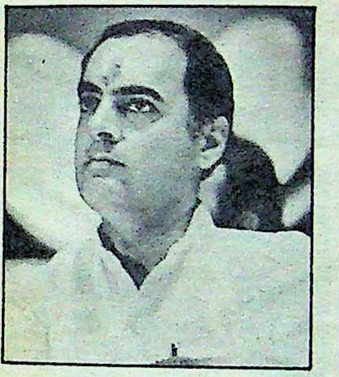

कोई चुनौती नहीं : राजीव गांधी

> **१९७७ में जनता पार्टी की जीत और २ वर्ष, ७ माह, २० दिन की अवधि में ही उसके बिखराव की त्रासदी मतदाता देख चुके हैं। इस बार फिर विपक्ष ने एक होने की हुंकार लगायी है। यदि विपक्ष का बिखराव उसकी नियति है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त विपक्ष ही कांग्रेस को पछाड़ सकता है। बशर्ते मतदाताओं में यह विश्वास पैदा हो जाये कि जीत के बाद भी विपक्ष एक रहेगा।**

भविष्य दांव पर : विश्वनाथ प्रताप सिंह

देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाला ८५ संसदीय और ४२५ विधानसभाई सीटों वाला उत्तर प्रदेश इस बार के आम चुनाव में राजनीतिक अंदेशों की चपेट में है। इस बार यहां न १९७७ जैसा गैरकांग्रेसवाद का उफान है और न ही १९८४ जैसी सहानुभूति की लहर। हाल ही में पनपी साम्प्रदायिकता को अलग करके देखें, तो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल बहुत कुछ १९६७ जैसा है। उस समय भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तब हिंदू मानसिकता ने जोर मारा था, जिसकी बदौलत भारतीय जनसंघ ने लोकसभा की १२ सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़े विपक्षी दल की हैसियत पायी थी। अब पुनः साम्प्रदायिक माहौल में होनेवाले आम चुनाव में भी हिंदू मानसिकता ने राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर अंगड़ाई ली है, जिसने हिंदुओं की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी के अरमान जगा दिये हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा की बढ़त को मिसाल के तौर पर परखा जाता है। १९६७ में सम्पूर्ण विपक्ष की ३८ सीटों पर जीत (प्राप्त वोट ६१.४२ प्रतिशत) के मुकाबले कांग्रेस ने ४७ सीटें (प्राप्त मत ३३.४२ प्रतिशत) पाकर किसी तरह अपनी लाज बचायी थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का न केवल प्राप्त मतों का प्रतिशत (३२.१५) घटा, वरन् १९६२ के मुकाबले ५० सीटों से भी उसे बेदखल होना पड़ा था।

कांग्रेस-इ अपराजेय नहीं : उत्तर प्रदेश को भले ही कांग्रेस का आधार राज्य कहा जाता है, लेकिन सफलता के शिखर के दो अपवादों—१९५२ और १९८४ के अलावा वोट की दृष्टि से यह प्रदेश कांग्रेस का मजबूत गढ़ कभी नहीं रहा। प्रथम महानिर्वाचन १९५२ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोकसभा की ८६ में से ८१ सीटें तथा विधानसभा की ४२९ में से ३९० सीटें हासिल करनेवाली कांग्रेस, उसके बाद (केवल १९८४ के अपवाद को छोड़कर) उतनी बड़ी सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकी। १९५२ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ५३ प्रतिशत और सम्पूर्ण विपक्ष को ४१.०४ प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ४९.७५ तथा विपक्ष को ४८.५३ प्रतिशत मत हासिल हुए। १९५७ के आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की ११ तथा विधान-सभा की १०४ सीटों से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस के हाथ से फिसलती सीटों का क्रम १९६२ के तीसरे महानिर्वाचन में भी जारी रहा। इस चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की ८ और विधानसभा की ३७ सीटें और खो दीं। लोकसभा के ८६ स्थानों में उसे ६२ और विधानसभा के ४२५ स्थानों में से २४९ स्थान ही मिल सके। इसी के साथ, जहां कांग्रेस के प्राप्त मतों में जबरदस्त गिरावट आयी, वहीं विपक्ष के मतों में भारी इजाफा हुआ। कांग्रेस के विरोध में ५७.५६ प्रतिशत मत पड़े, लेकिन इन मतों के बंटवारे के कारण ही ३८.०२ प्रतिशत मत पाकर भी कांग्रेस संसदीय सत्ता में बनी रही। इसी तरह विधानसभा में विपक्ष को मिले ५८.१५ प्रतिशत (१८१ सीटें) के मुकाबले ३६.३ प्रतिशत (२४९ सीटें) मत हासिल कर कांग्रेस की सत्ता प्रदेश में बरकरार रही।

१९६७ के चौथे आम चुनाव में तो कांग्रेस लगभग उखड़ने सी लगी। लोकसभा के ८५ स्थानों में कांग्रेस ३३.४२ प्रतिशत मत प्राप्त कर ४७ सीटों तक सिमट गयी। वहीं विपक्ष ६१.४२ प्रतिशत मत बटोर कर पहली बार संसद की ३८ सीटों पर काबिज हुआ। विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ३२.१५ प्रतिशत मत प्राप्त कर १९९ स्थानों पर जीत सकी थी। १९७७ को छोड़कर यह अब तक के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे कम सीटें प्राप्त करनेवाला चुनाव रहा। इसके विपरीत ६१.२८ प्रतिशत मत प्राप्त कर विधानसभाई चुनाव में भी प्रथम बार २२६ सीटें प्राप्त करने में विपक्ष ने कामयाबी हासिल की थी। इस चौथे संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आया। उसने ७७ स्थानों पर चुनाव लड़ा था और २२.१५ प्रतिशत मत प्राप्त कर १२ स्थानों पर विजय दर्ज की थी।

कांग्रेस में विघटन : १९६७ के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांतिदल का गठन कर लिया। तब पहली बार उत्तर प्रदेश में संविद सरकार बनी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के भी दो फाड़ हो गये। एक कांग्रेस-ज (जगजीवन राम) और दूसरी कांग्रेस-न (निजलिंगप्पा)। १९६७ का विधानसभाई चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। यह पहला अवसर था, जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। विरोधी पार्टियों द्वारा सरकार बनाने में तालमेल न हो पाने का ही नतीजा था कि तत्कालीन राज्यपाल वी गोपालरेड्डी ने विधानसभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी होने के नाते कांग्रेस के चन्द्रभानु गुप्त को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। श्री गुप्त की १४ मार्च, १९६७ को बनी इस सरकार की मियाद केवल १८ दिन की रही, क्योंकि १ अप्रैल, १९६७ को चौधरी चरण सिंह ने सत्तारूढ़ दल के १७

सदस्यों के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किये जाने के पक्ष में विरोधी दल का साथ देकर कांग्रेस को अल्पमत में ला दिया था। ३ अप्रैल, १९६७ को चौधरी चरण सिंह ने संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन आयाराम-गयाराम के बढ़ते माहौल ने १७ फरवरी, १९६८ को चौधरी चरण सिंह को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया। यह वह मौका था, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार एक साल (२५ फरवरी, १९६८ से लेकर २६ फरवरी, १९६९) तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

पांच वर्ष में पांच मुख्यमंत्री: इसके बाद १९६९ में हुए विधानसभा के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने १९६७ के मुकाबले १२ सीटों की बढ़त हासिल कर ली थी। ४२० स्थानों पर हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने ३३.६८ प्रतिशत मत प्राप्त कर २११ सीटें जीती, जबकि विपक्ष ६३.०४ प्रतिशत मत पाकर भी २०९ सीटों पर ही काबिज हो सका था। ५ वर्ष, ६ दिन की अवधिवाली इस विधानसभा को ५ मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और दो बार राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजरना पड़ा।

१९७१ के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व बड़े पैमाने पर हुए दल-बदल के कारण उत्तर प्रदेश के संसद में प्रतिनिधित्व करनेवाले ८५ सदस्यों में कांग्रेस-जे के ४७ से घटकर ४३ सदस्य, तथा कांग्रेस-एन के ७, जनसंघ के ११, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ७, भारतीय क्रांति दल के ६, कम्युनिस्ट पार्टी का एक और पांच निर्दलीय सदस्य रह गये थे। १९७१ का लोकसभा चुनाव कांग्रेस-जे ने उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से लड़ा था। गरीबी हटाओ और प्रीविपर्स समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण और प्रलोभन भरे नारों के साथ कांग्रेस-जे ने ७८ स्थानों पर अपने उम्मीदवार उतारे और ७३ सीटें हथिया लीं। सात स्थान उसने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़े थे, जिसने ३.७ प्रतिशत मत प्राप्त कर ४ सीटें जीतीं। कांग्रेस को प्राप्त ४८.६ प्रतिशत मतों के मुकाबले विपक्ष ने ४८.८५ प्रतिशत मत हासिल करके भी केवल १२ स्थान ही पाये। कांग्रेस से अलग हुआ निजलिंगप्पा गुट ४४ स्थानों पर लड़ा, लेकिन मात्र एक सीट जीतकर वह नामलेवा पार्टी बनकर रह गया। सर्वाधिक नुकसान जनसंघ को हुआ। उसकी न केवल सदस्य संख्या घटकर १२ से ४ रह गयी, वरन् प्राप्त मतों का प्रतिशत भी सिमटकर २२ से १२ रह गया। नवगठित भारतीय क्रांतिदल को भी १२.६९ प्रतिशत मत पाकर केवल एक स्थान जीत कर ही संतोष करना पड़ा।

१९७४ में छठी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने १९६९ के मुकाबले ५ सीटें और हासिल कर अपनी सदस्य संख्या २१६ कर ली। ४२४ स्थानों पर हुए इस चुनाव में विपक्ष को प्राप्त मतों का प्रतिशत कांग्रेस को प्राप्त मतों के प्रतिशत (३२.२९) से दो गुना अधिक (६४.७१) था। लेकिन तब भी १९६९ की अपेक्षा एक सीट गंवाकर २०८ स्थानों पर ही जीत सकी। विपक्ष से मात्र ८ सीटों की बढ़त हासिल करने वाली कांग्रेस की सरकार बनी। यह छठी विधानसभा ५ वर्षों की अपनी निर्धारित कालावधि पूरा न कर सकी। ३ वर्ष १ माह और २८ दिन वाली यह विधानसभा दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और दो बार के राष्ट्रपति शासन से गुजरी।

जनता आंधी: १९७७ के आम चुनाव में जनता-आंधी एकतरफा बही। इस एकतरफा लहर से लोकसभा की ८५ सीटें नवगठित संयुक्त दल जनता पार्टी की झोली में सिमट आयी। इंका को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मात्र २५ प्रतिशत मत ही हासिल हो सके थे। इसी वर्ष हुए विधानसभा के चुनाव में भी काफी प्रयासों के बाद भी कांग्रेस ३२.३२ प्रतिशत मत हासिल कर किसी तरह ४२३ में ४७ सीटें पा सकी थी, जबकि विपक्ष ने ६६.०७ प्रतिशत मत बटोरकर ३७६ सीटों पर कब्जा किया था। यह पहला मौका था, जब देश, प्रदेश में विपक्ष को सत्तासुख की प्राप्ति हुई थी, लेकिन पद की लालसा और एक जुट हुई पार्टियों की लामबंदी ने ऐसी स्थिति ला दी कि विपक्ष की यह सरकार ५ वर्ष के कार्यकाल से पहले ही ढह गयी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने २ वर्ष ७ माह, २० दिन तक सत्ता सुख भोगा, दो मुख्यमंत्री बने और अन्ततः यह जनता सरकार राष्ट्रपति शासन (१९ फरवरी से ९ जून, १९८० तक) के साथ विलीन हो गयी।

विपक्ष के बिखराव और आपसी टकराहट को आम जनता ने बहुत बारीकी से परखा और इसी के बाद १९८० के आम चुनाव में जनता ने राजनीति की एकल पार्टी कांग्रेस को ही तरजीह दी। विपक्ष की उस टूटन का फायदा कांग्रेस ने १९८० के संसदीय और विधानसभाई चुनावों में उठाया। १९७७ में जब कांग्रेस की जीत लोकसभा में शून्य रही, वहीं १९८० में वह १०.९० प्रतिशत मतों की बढ़ोतरी (३५.९०) पाकर ५१ सीटों पर काबिज हो गयी। दूसरी ओर, विपक्ष ६१.८

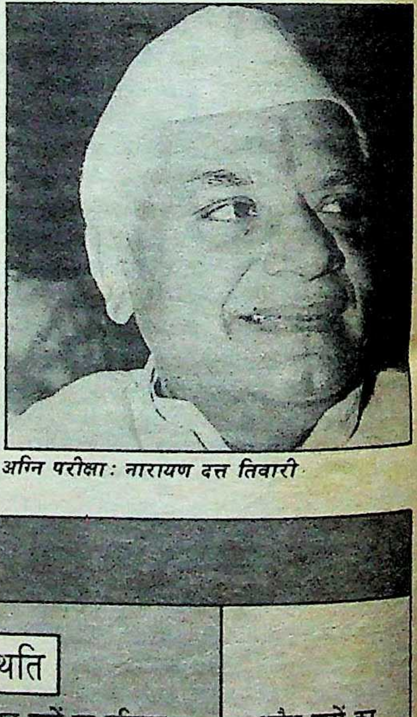

अग्नि परीक्षा: नारायण दत्त तिवारी

लोकसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और विपक्ष की स्थिति

वर्ष	कुल सीटें	चुनाव हुआ	कांग्रेस को	विपक्ष को मिली सीटें	प्राप्त मतों का प्रतिशत कांग्रेस	प्राप्त मतों का प्रतिशत विपक्ष	अवैध मतों का प्रतिशत
१९५२	८६	८६	८१	५	५३.०	४१.०४	५.९६
१९५७	८६	८५	७०	१५	४६.३	५०.५२	३.१८
१९६२	८६	८६	६२	१४	३८.२	५७.५६	४.२४
१९६७	८५	८५	४७	३८	३३.४२	६१.४२	५.१६
१९७१	८५	८५	७३	१२	४८.६	४८.८५	२.५५
१९७७	८५	८५	—	८५	२५.००	७२.८४	२.११
१९८०	८५	८५	५१	३४	३५.९०	६१.८	२.३०
१९८४	८५	८५	८३	२	५६.६०	४१.३७	२.०३

प्रतिशत मत पाकर भी १९७७ के मुकाबले ५१ सीटें खोकर ३४ स्थान ही पा सका था। इस समय तक कांग्रेस-अर्स भी एक पार्टी बन चुकी थी, जिसके ३५ उम्मीदवार लड़े, जिसमें ३४ की तो जमानत ही जब्त हो गयी। जनता पार्टी-ज (जगजीवनराम) ने भी ८५ सीटों पर जोर आजमाइश की थी, लेकिन इस पार्टी में तत्कालीन जनसंघियों के होने के बावजूद उसे २२.९६ प्रतिशत मत और तीन सीटें ही मिल सकीं। इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी। उसने ७९ स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, जिनमें २९ को सफलता मिल गयी थी। इसी तरह विधानसभा के भी उसी वर्ष हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने खासी बढ़त हासिल की थी। ४२१ सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने विपक्ष को प्राप्त ११५ सीटों के मुकाबले ३०६ सीटों पर काबिज होकर सत्ता की पुनर्प्राप्ति की थी। यह स्थिति तब थी, जब संयुक्त विपक्ष ने कांग्रेस को प्राप्त ३७.७८ प्रतिशत मतों के मुकाबले ६०.५२ प्रतिशत मत अर्जित किये थे।

सहानुभूति लहर : १९७७ की जनता लहर की तरह १९८४ में हुए आठवें लोकसभा और नौवीं विधानसभा चुनाव के समय भी श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर थी। इस चुनाव में इंका ने ५६.६० प्रतिशत मत हासिल कर संसद की ८५ से ८३ सीटों पर कब्जा कर लिया था। चरण सिंह का लोकदल ७३ स्थानों पर लड़ा और केवल चरण सिंह की परम्परागत सीट बागपत के अतिरिक्त वह एटा में ही सफलता हासिल कर सका। भाजपा भी ५० स्थानों पर लड़ी। उसे ६.३८ प्रतिशत मत मिले, लेकिन उसके ४० प्रत्याशियों को अपनी जमानत गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर लोकदल को छोड़कर अन्य विपक्षी दल बुरी तरह धराशायी हो गये।

विधानसभा चुनाव

वर्ष	कुल सीटें	चुनाव हुआ	कांग्रेस को मिली सीटें	विपक्ष को मिली सीटें	प्राप्त मतों का प्रतिशत		अवैध मतों का प्रतिशत
					कांग्रेस	विपक्ष	
१९५२	४३०	४२९	३९०	३९	४७.९५	४८.५३	३.५२
१९५७	४३०	४३०	२८६	१४४	४२.४२	५४.१५	३.४३
१९६२	४३०	४३०	२४९	१८१	३६.३	५८.१५	५.५५
१९६७	४२५	४२५	१९९	२२६	३२.१५	६१.२८	६.५७
१९६९	४२५	४२०	२११	२०९	३३.६८	६३.०४	३.२८
१९७४	४२५	४२४	२१६	२०८	३२.२९	६४.७१	३.००
१९७७	४२५	४२३	४७	३७६	३२.३२	६६.०७	१.६१
१९८०	४२५	४२१	३०६	११५	३७.७८	६०.५२	१.७४
१९८५	४२५	४२२	२६८	१५४	३९.३१	५९.२१	१.४८

विपक्ष की उम्मीद: मुलायम सिंह यादव

१९८४ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का यह रिकार्ड ४ माह बाद मार्च, १९८५ में हुए विधानसभा के चुनाव तक कायम न रह सका। इस समय तक सहानुभूति की बयार मंद हो गयी थी। यही वजह थी कि इस चुनाव में कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले ३८ सीटें गंवा कर ६८ सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और कांग्रेस को जहां ४ माह पूर्व संसदीय चुनाव में ५६.६० प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, वहीं विधानसभा में उसे सिर्फ ३९.३१ प्रतिशत मत ही मिले। विपक्ष ने संसदीय चुनाव (४१.३७ प्रतिशत) से अधिक ५९.२१ प्रतिशत मत प्राप्त कर १५४ सीटें जीती थीं। इस चुनाव में भी लोकदल ने सर्वाधिक ८४ सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत अर्जित की थी, जबकि भाजपा को १५, जनता पार्टी को २०, भाकपा को ६, माकपा को २, कांग्रेस-जे को २, निर्दलीय उम्मीदवारों को २५ सीटें मिली थीं।

अब कोई लहर नहीं: पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसी परिस्थिति इस बार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत साफ नहीं है। यदि इस प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के इतिहास पर गौर किया जाये, तो आज का राजनीतिक माहौल १९६७ से बहुत हद तक मेल खाता है। उस समय भी जनता कांग्रेस से नाराज तो थी, किन्तु उसे कोई विकल्प नहीं दिखायी पड़ रहा था। यही वजह थी कि ४७ सीटें प्राप्त कर कांग्रेस ने लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त कर लिया था, किन्तु उत्तर प्रदेश सहित ८ राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पायी थी। तब के विधानसभा चुनाव में जनसंघ ९८ स्थान हासिल कर प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी थी। आज जनसंघ की जगह भाजपा ने ले ली है।

लेकिन इस बार मतदाता राजीव सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन उनके सामने यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर इंका का विकल्प कौन है? १९७७ में जनता पार्टी की जीत और २ वर्ष, ७ माह, २० दिन की अवधि में ही उसके बिखराव की त्रासदी मतदाता देख चुके हैं। इस बार फिर विपक्ष ने एक होने की हुंकार लगायी है। यदि विपक्ष का बिखराव उसकी नियति नहीं है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त विपक्ष ही कांग्रेस को पछाड़ सकता है। बशर्ते मतदाताओं में यह विश्वास पैदा हो जाये कि जीत के बाद भी विपक्ष एक रहेगा।

—अजय कुमार

वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र

गढ़ टूटने के आसार

बिहार ही वह प्रदेश है, जहां से उठी जयप्रकाश की आंधी ने १९७७ में न केवल बिहार के कांग्रेसी गढ़ को ध्वस्त कर दिया था, बल्कि कांग्रेस-इ दिल्ली के तख्त को भी नहीं बचा पायी थी। इस बार १९७७ जैसी लहर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश संगठन में जैसी गुटबाजी अभी भी विद्यमान है, उसे देखते हुए क्या ऐसे आसार बन रहे हैं कि कांग्रेस की दिग्गज हस्तियों को भी अपनी-अपनी सीट बचाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ जायेंगे? 'माया' की तहकीकात:

चुनाव की दस्तक के साथ बिहार के चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक गरमाहट तेज होने लगी है। स्कूल, कालेज, सरकारी दफ्तरों एवं गांव-शहर के प्रत्येक नुक्कड़ व चौराहों तक पर चुनावी—हिसाब-किताब की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। किस एमपी या किस एमएलए ने पिछले पांच सालों में कितना काम किया, किसने क्या वायदे किये—जैसी बातें भी लोग याद करने लगे हैं। चुनाव जीतने के लिए कौन-सा हथकंडा इस्तेमाल किया जाये, यह अभी से ही संभावित उम्मीदवारों को परेशान किये हुए है। इस चुनाव में किसी के पक्ष में हवा नहीं है। हवा थमी हुई है। लोग-बाग भी दम साधे बैठे हुए हैं। चुनाव में क्या होगा, इसका अनुमान दिग्गज राजनीतिक खिलाड़ियों को भी नहीं लग रहा है। बिहार के वीआईपी चुनाव क्षेत्रों का तो पूछना ही क्या?

बक्सर का हाल: अपने सात दिवसीय व्यापक जनसंपर्क अभियान पर निकले प्रोफेसर केके तिवारी को पिछले दिनों सिर्फ बिहिया में ही नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। यों तो इन्हें लोकसभा में 'जीरो आवर का हीरो' कहा जाता रहा है, लेकिन फिलवक्त ये अपने चुनाव क्षेत्र में फिसड्डी हो रहे हैं। अब तो उनके संसदीय क्षेत्र बक्सर के हर शख्स की जुबान पर यही चर्चा है कि क्या प्रोफेसर तिवारी तीसरी बार यहां से सांसद बनेंगे? वैसे इस क्षेत्र की विशेषता रही है कि तिबारा यहां से कोई चुनाव जीत नहीं सका।

१९५२ और १९५७ के संसदीय चुनाव में डुमरांव के महाराजा कमल सिंह स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बक्सर से विजयी हुए थे। वर्ष १९६२ के आम चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से अनंत प्रसाद शर्मा निर्वाचित हुए। लेकिन १९६७ में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार १९६७ में बने डा० रामसुभग सिंह। चुनाव में वे भारी बहुमत से जीते। पुन: १९७१ के मध्यावधि चुनाव में अनंत प्रसाद शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। १९७१ में डा० रामसुभग सिंह, संगठन कांग्रेस में थे।

आपातकाल के बाद १९७७ के चुनाव में अनंत प्रसाद शर्मा बक्सर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के नेता रामानंद तिवारी से चुनाव हार गये। ढाई वर्ष के उपरांत १९८० के चुनाव में इंका के प्रोफेसर केके तिवारी बक्सर से निर्वाचित हुए। इससे पहले केके तिवारी पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता थे।

पुन: १९८४ के चुनाव में कांग्रेस-इ ने बक्सर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए केके तिवारी को ही अपना उम्मीदवार घोषित किया। चुनाव में केके तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्ट पार्टी के तेज नारायण सिंह को पचपन हजार से भी ज्यादा वोटों से पराजित कर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। उन्हें राजीव गांधी ने केंद्रीय राज्यमंत्री का दायित्व सौंपा। बाद में उन्हें मंत्री का पदभार छोड़ना पड़ा। लेकिन केके तिवारी को पुन: केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहले उन्हें विदेश राज्यमंत्री और बाद में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री का भार दिया गया।

बक्सर संसदीय क्षेत्र में छह विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले चुनाव में शाहपुर, ब्रह्मपुर, डुमरांव और बक्सर विधानसभा क्षेत्रों में इंका विजयी हुई थी, जबकि सुरक्षित क्षेत्र राजपुर में भाजपा तथा जगदीशपुर में लोकदल। इन दिनों शाहपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे। किंतु केंद्रीय श्रममंत्री बन जाने से दुबे ने शाहपुर विधानसभा की सीट छोड़ दी। इस खाली सीट पर फिर उपचुनाव नहीं हुआ।

बक्सर संसदीय सीट ब्राह्मणबहुल सीट है। परंतु अन्य पिछड़ी जातियों में यादव और उच्च जातियों में राजपूत यहां निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तकरीबन नौ लाख मतदाताओं के इस क्षेत्र में जातीय आधार पर सर्वेक्षण से पता चलता है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रतिशत ३८, ब्रह्मपुर में १३, बक्सर में २०, राजपुर में १० तथा डुमरांव में १५ है। यादव मतदाताओं की स्थिति इस प्रकार है—शाहपुर में १३ प्रतिशत, ब्रह्मपुर में २१ प्रतिशत, बक्सर में २० प्रतिशत, राजपुर में १७ प्रतिशत, डुमरांव में २० प्रतिशत और जगदीशपुर में २० प्रतिशत। इस क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाता हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और चुनाव में जीत-हार का फैसला बहुत कुछ ब्राह्मणों पर ही निर्भर रहा है। यही कारण है कि पिछले आठ संसदीय चुनावों में से पांच बार कांग्रेस इस क्षेत्र से विजयी हुई है।

बक्सर के किसान भी केके तिवारी से अप्रसन्न हैं। उनके लिए सुखाड़ में न तो ट्यूबवेल का व्यापक प्रबंध किया गया और न ही सोन-सिस्टम का आधुनिकीकरण। हालांकि

यों तो इन्हें लोकसभा में 'जीरो आवर का हीरो' कहा जाता रहा है, लेकिन फिलवक्त ये अपने चुनाव क्षेत्र में फिसड्डी हो रहे हैं।

केके तिवारी

तपेश्वर सिंह

आजाद को मुख्यमंत्री की कुरसी से हटवाकर तपेश्वर जेल जाने से तो बच गये, लेकिन लगता है कि लोकसभा में नहीं पहुंच पायेंगे।

१९८४ के चुनाव में केके तिवारी ने सोन-सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इलाके के किसानों से वायदा भी किया था। इस सिस्टम के आधुनिकीकरण से बक्सर में धान की पैदावार दूनी हो जाती।

फिर वायदों का पुलिंदा लिये घूम रहे हैं केके तिवारी। अपने जनसंपर्क अभियान के क्रम में तिवारी ने घोषणा की है कि बक्सर को अब औद्योगिक नक्शे पर लाया जायेगा। उन्होंने बिहिया में दूरदर्शन केंद्र खोलने, सिकरिया के पास हाल्ट स्टेशन बनवाने, ग्यारह अप तथा बारह डाउन ट्रेन का बिहिया में ठहराव करने एवं बिहिया में साठ किलो वाट क्षमता का ग्रीड स्टेशन बनवाने का ऐलान किया। पर तिवारी के इन आश्वासनों का बक्सर के मतदाताओं पर पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ रहा।

विक्रमगंज/सासाराम: "वोट का बक्सा खाली भेज देना, लेकिन किसी माफिया को भूलकर भी संसद या विधानसभा में जाने का मौका न देना।" रोहतास जिले के विक्रमगंज एवं सासाराम संसदीय क्षेत्र में २८ जून की चिलचिलाती धूप में अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने जब यह आह्वान किया, तो एक साथ हजारों-हजार हाथ उठे और नारे लगे, "किसी सूरत में माफिया को जीतने नहीं देंगे।" आजाद का यह अनोखा चुनाव-अभियान सहकारिता कुबेर व विक्रमगंज के मौजूदा इंका सांसद तपेश्वर सिंह के लिए बिलकुल अप्रत्याशित था। आजाद को मुख्यमंत्री की कुरसी से हटवाकर तपेश्वर जेल जाने से तो बच गये, लेकिन लगता है कि लोकसभा में नहीं पहुंच पायेंगे।

यकीनन, रोहतास जिले के दोनों संसदीय क्षेत्रों-सासाराम एवं विक्रमगंज-पर लोगों की आंखें गड़ी हुई हैं। इन दोनों सीटों का प्रारंभ से ही राष्ट्रीय महत्व रहा है। एक ओर सासाराम (सुरक्षित क्षेत्र) से स्वर्गीय जगजीवन राम जीवनपर्यंत चुनाव लड़ते एवं जीतते रहे, वहीं दूसरी ओर विक्रमगंज से डा० रामसुभग सिंह, शिवपूजन शास्त्री, राम अवधेश सिंह तथा तपेश्वर सिंह चुनाव जीतते-हारते रहे हैं।

मतदाता शहाबुद्दीन से काफी खफा हैं। उन्होंने दस सूत्री विकास का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ।

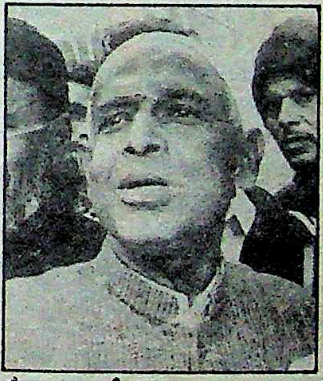
सैयद शहाबुद्दीन

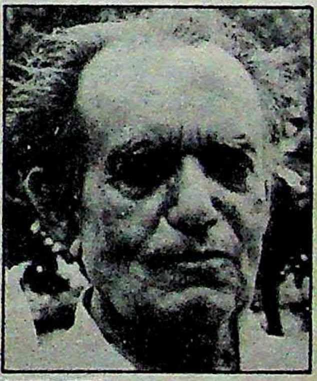
अब्दुल गफूर

जो सांसद बनकर दिल्ली गया, वह दुबारा मुंह दिखाने नहीं आया। यही हालत सिवान के मौजूदा सांसद अब्दुल गफूर की भी रही है।

विक्रमगंज चुनाव क्षेत्र की विशेषता रही है कि शुरू से ही यहां राजपूत एवं यादवों में टक्कर होती रही है। १९५२, १९५७ तथा १९६२ में यहां से कांग्रेस टिकट पर डा० रामसुभग सिंह जीतते रहे। डा० सिंह राजपूत थे और शिवपूजन शास्त्री यादव। तीनों चुनावों में शिवपूजन शास्त्री की हार हुई थी। लेकिन १९६७ में डा० रामसुभग सिंह ने अपना क्षेत्र बदल दिया और बक्सर चले गये। लिहाजा १९६७ के चुनाव में हरगोविंद मिश्र को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन यह सीट शिवपूजन शास्त्री ने हथिया ली। शिवपूजन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए थे। १९७७ में जनता पार्टी ने राम अवधेश सिंह को टिकट दिया। राम अवधेश सिंह ने कांग्रेसी उम्मीदवार डा० रामसुभग सिंह को चारो खाने चित्त कर दिया। आपातकाल के बाद डा० रामसुभग सिंह कांग्रेस में आ गये थे। १९७९ में डा० रामसुभग सिंह की मृत्यु के उपरांत विक्रमगंज में राजपूतों के नेता बने सहकारिता सम्राट तपेश्वर सिंह। वर्ष १९८० एवं १९८४ में तपेश्वर सिंह इंका उम्मीदवार बने और और जीते भी। हालांकि दोनों चुनावों में राम अवधेश सिंह से तपेश्वर की लड़ाई कांटे की रही। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद व पूर्व प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष तारिक अनवर के हाल के सासाराम एवं डिहरी दौरे से तपेश्वर विरोधी गुट मजबूत हुआ है। सत्येंद्र नारायण सिंह जब १० जुलाई को सासाराम गये, तो उन्होंने तपेश्वर सिंह की घोर उपेक्षा की। हाल में बिहार सरकार ने सहकारिता घोटाले के मामले में फिर तपेश्वर पर केस दर्ज किया है। वैसे भी तपेश्वर सिंह का विरोध विक्रमगंज में दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

विपक्ष की स्थिति विक्रमगंज में साफ नहीं है। लेकिन जब से आईपीएफ ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से विक्रमगंज में फ्रंट सबसे आगे है। केंद्रीय गुप्तचर टीम की एक रिपोर्ट के अनुसार विक्रमगंज में आईपीएफ के सक्रिय कार्यकर्ता पचपन हजार के करीब हैं।

बहरहाल, आगामी चुनाव में इंका के सामने सबसे बड़ी परेशानी होगी रोहतास उद्योग समूह का अभी तक बंद रहना, आरा-सासाराम रेल लाइन का निर्माण न होना और आईपीएफ के झंडे तले हरिजनों का जागरूक व एकजुट होना। इसी से लगता है कि इस बार विक्रमगज सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

किशनगंज: किशनगंज से मौजूदा सांसद शहाबुद्दीन इस बार सांसत में हैं। बांग्ला देश के सीमावर्ती होने से पूर्णिया जिले के किशनगंज संसदीय क्षेत्र का अपना अलग स्थान है। यह मुसलमानबहुल निर्वाचन क्षेत्र है। यहां कुल वोटरों में साठ प्रतिशत मुसलमान एवं चालीस प्रतिशत हिंदू हैं। लिहाजा, मुसलिम मत किशनगंज में निर्णायक रहा है।

१९८४ की सहानुभूति लहर में यहां से कांग्रेस-इ के जमीलुर्रहमान भारी मतों से विजयी हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद वहां उपचुनाव हुआ। जनता पार्टी ने सैयद शहाबुद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया। अन्य विपक्षी दलों का समर्थन भी शहाबुद्दीन को मिला। नतीजतन, शहाबुद्दीन यह चुनाव जीत गये। पर १९८५ और १९८९ के बीच परिस्थितियां काफी बदल गयी हैं। शहाबुद्दीन जनता दल से रिश्ता तोड़कर 'इंसाफ पार्टी' का गठन कर चुके हैं। पिछले उपचुनाव के समय किये गये वायदों को पूरा न करने से भी मतदाता शहाबुद्दीन से काफी खफा हैं। उन्होंने दस सूत्री विकास का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ।

शहाबुद्दीन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किशनगंज को जिला बनाने की थी। जिला बनना तो दूर रहा, करीब एक वर्ष से यहां अनुमंडल अधिकारी का पद भी रिक्त है। उनकी अन्य घोषणाओं में जूट मिल स्थापित करवाना, खगड़ा नदी पर ओवरब्रिज बनवाना, इलाके में सड़कों और रेलों का विस्तार करवाना, उद्योग खुलवाना आदि प्रमुख थे।

१९८५ में शाहबानो का मामला गर्म था। जूट की कीमत भी काफी गिर गयी थी। किशनगंज में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है। लिहाजा, जनता कांग्रेस से कुपित थी। शहाबुद्दीन को बेशक इसका लाभ मिला था। पर इस बार ऐसी कोई

संभावना नहीं दिखती। उनके अधिकतर कार्यकर्ता भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारी है।

विपक्षी दलों में भाजपा के प्रत्याशी भाई ताराचंद हैं। भाजपा ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू भी कर दिया है। जहां तक जनता दल का सवाल है, वह मुन्ना मुश्ताक, तसलीमुद्दीन और लखनलाल कपूर के खेमों में विभाजित है। इनमें मुन्ना मुश्ताक और तसलीमुद्दीन विधायक हैं। लेकिन तसलीमुद्दीन पर सांप्रदायिक होने का आरोप है, जबकि मुन्ना को दोनों समुदायों का समर्थन प्राप्त है। बहरहाल, जनता दल, भाजपा के उम्मीदवार और इंसाफ पार्टी से शहाबुद्दीन की उम्मीदवारी विपक्ष के वोट को तीन हिस्सों में बांटेगी। इसलिए कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में चढ़ाने के लिए आशान्वित है।

सिवान: मात्र जनता लहर को छोड़कर सिवान संसदीय क्षेत्र प्रारंभ से ही कांग्रेस का रहा है। जनता लहर के दौरान देशरत्न डा० राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद यहां से संसदीय चुनाव जीते थे। लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि १९५२ में सिवान की जो स्थिति थी, वही आज भी है। एक बार जो सांसद बनकर दिल्ली गया वह दुबारा मुंह दिखाने नहीं आया। यही हालत सिवान के मौजूदा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल गफूर की भी रही है।

सर्वेक्षण से पता चला है कि इंका के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। जिले की तीन चीनी मिलों में से पचरुखी चीनी मिल अरसे से बंद पड़ी है और सिवान शहर में जो दो मिलें हैं, वे साल में तीन महीने ही चलती हैं। बाकी नौ महीने मिल के कर्मचारी भूखे मरते हैं। साथ ही तीनों मिलों पर किसानों के लाखों के बकाये भी हैं। मिलों की स्थिति में सुधार के लिए तकरीबन पंद्रह वर्षों से सांसद व विधायक कर्मचारियों को आश्वासन देते रहे हैं। उनके आश्वासन केवल चुनावी आश्वासन बनकर रह जाते हैं। इसीलिए एसकेजी शुगर मिल के एक कर्मचारी ने 'माया' को बताया, "इस बार वोट झूठे वायदे करनेवालों को नहीं देंगे।"

बेरोजगार युवकों के लिए जिले में खुलनेवाली सूत मिल आशा की केंद्र थी। सूत मिल का भवन सिवान के श्रीनगर मुहल्ले में बनकर तैयार है, लेकिन उसे कब चालू किया जायेगा, कोई कह नहीं सकता। इस मिल के खुल जाने से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होते।

जिले की जनता डा० राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना न होने से सत्तापक्ष के नेताओं से सख्त नाराज है। सिवान शहर में एक भी उद्यान नहीं है। राजेंद्र स्टेडियम है भी, तो किसी काम का नहीं। हाल ही एक फुटबाल मैच के दौरान राजेंद्र स्टेडियम की गैलरी का एक भाग टूटकर गिर गया, जिससे सैकड़ों लोग जख्मी हो गये थे। लेकिन स्टेडियम पर आज तक किसी नेता की नजर नहीं गयी।

बेगूसराय: बेगूसराय संसदीय क्षेत्र पर सबकी आंखें टिकी हुई हैं। १९८४ के चुनाव में यहां से भारत सरकार की मौजूदा राज्य मंत्री कृष्णा शाही जीती थीं। उन्होंने जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिलदेव सिंह को दो लाख, अस्सी हजार वोटों से पराजित किया था। इस जिले में बेगूसराय संसदीय सीट के अलावा बलिया संसदीय क्षेत्र भी है। बलिया से चंद्रभानु देवी इंका सांसद हैं। चंद्रभानु देवी ने विगत चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के सूर्यनारायण सिंह को एक लाख, चौबीस हजार वोटों से शिकस्त दी थी।

चुनावी चर्चा जब शुरू हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने अन्य क्षेत्रों की तरह बेगूसराय में भी पर्यवेक्षक भेजा। गत २३ जून को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी-इ के महामंत्री केपी तिवारी यहां पर्यवेक्षक बनकर आये थे। जिले के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक बुलायी और कृष्णा शाही के कार्यों की समीक्षा की।

मतदाताओं को लुभाने की कोशिश: कृष्णा शाही

१९८४ के लोकसभा चुनाव में कृष्णा शाही ने जिले के मतदाताओं से अनेक वायदे किये थे। उनमें बेगूसराय शहर में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना, टीवी रिले सेंटर खुलवाना आदि प्रमुख थे। कृष्णा शाही ने जनता से किये कुछ वायदों को पूरा किया, लेकिन बरौनी क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कारखाने के निर्माण पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लिहाजा, मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनसे क्षुब्ध है। हालांकि इन दिनों लगातार कृष्णा शाही प्रचार कर रही हैं कि जल्द ही दस अरब रुपए की लागत से इस कारखाने का निर्माण कर हजारों लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

बलिया संसदीय सीट के अंतर्गत छह विधानसभाई क्षेत्र हैं। इनमें बलिया एवं बरियारपुर तो कांग्रेस के कब्जे में हैं, जबकि अलौली, बखरी, बछवाड़ा व बरौनी से विरोधी दल के पशुपति कुमार, राम विनोद पासवान, अयोध्या प्रसाद तथा शकुंतला देवी विधायक हैं। राम विनोद, अयोध्या और शकुंतला देवी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं।

बहरहाल, सर्वेक्षण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि बलिया में कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट के बीच कांटे की लड़ाई होगी। जिसकी भी जीत हो, जीत-हार का फासला बहुत ही कम रहेगा।

आरा: अगस्त १९८९ के अंतिम सप्ताह में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र ने आरा की कुछेक जनसभाओं में पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री बलिराम भगत को अगले संसदीय चुनाव में फिर कांग्रेस-इ का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, तो उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। आरा के वीर कुंवर सिंह पार्क की सभा में तो स्थानीय लोगों ने बलिराम भगत के हाथ से माइक तक छीन लिया और उनके विरोध में नारे लगाये गये। बलिराम भगत के लिए ये घटनाएं आश्चर्यजनक नहीं थीं। जून १९८९ में भी बड़हरा से आरा लौटते समय क्रुद्ध भीड़ ने उनकी गाड़ी रोककर ईंट-पत्थर चलाया था और उन पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया था। लोगों का कहना था कि बलिराम भगत ने १९८४ के चुनाव के वक्त भोजपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना, सोन नहर के आधुनिकीकरण और गंगा के कटाव से बचाने के वायदे किये थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बलिराम भगत दिल्ली जो गये, तो चार साल तक फिर मुंह दिखाने नहीं आये।

वादाखिलाफी का आरोप: बलिराम भगत

आरा संसदीय सीट पर १९७७ और १९८० के चुनाव को छोड़कर १९५२ से लगातार कांग्रेस की जीत होती रही है। १९७७ और १९८० में जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रदेव प्रसाद वर्मा चुने गये थे। लेकिन १९८४ में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा बलिराम भगत से हार गये। आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़हरा, आरा, सहार, संदेश, मनेर और पालीगंज छह विधानसभाई क्षेत्र हैं। इनमें संदेश और बड़हरा पर जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि आरा, मनेर व पालीगंज सीट कांग्रेस के हाथ में है। आरा के विधायक डा० मोहम्मद ईसा और सहार की विधायिका श्रीमती ज्योति बिहार सरकार के मंत्री हैं।

आरा संसदीय सीट के मतदाताओं में यादव एवं कोइरी जाति की संख्या काफी है। कांग्रेसी सांसद बलिराम भगत यादव हैं, जबकि चंद्रदेव प्रसाद वर्मा कोइरी।

इधर इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने आरा में अपनी जमीन पोख्ता कर रखी है। रामेश्वर प्रसाद आरा क्षेत्र के आईपीएफ के उम्मीदवार हैं। जिले के तमाम ग्रामीण इलाकों में वे

पदयात्रा कर रहे हैं। इनका जातिगत आधार भी है। वैसे आईपीएफ की शक्ति आरा में काफी बढ़ी भी है। दूर-दराज के गांवों में इसके अनेक कार्यकर्ता चुनावी दंगल में जोर आजमाइश की तैयारी में लग गये हैं। लेकिन, अगले चुनाव में आरा संसदीय सीट का क्या होगा, राजनीतिक पंडित भी कुछ साफ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

दरभंगा: उत्तरी बिहार के दरभंगा संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। इस मैथिल ब्राह्मणबहुल क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह रही है कि यहां से कोई शख्स दुबारा चुनाव जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंच सका। १९७१ में केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र दरभंगा से सांसद हुए थे। किंतु १९७५ में उनकी हत्या हो गयी। लिहाजा, उन्हें फिर क्षेत्र में जाने का मौका ही नहीं मिला।

१९७७ की जनता लहर में सुरेंद्र झा सुमन ने कांग्रेस के राधानंदन झा को एक लाख, पचहत्तर हजार मतों से हराकर विजय प्राप्त की थी। १९८० के चुनाव में कांग्रेस-इ के हरिनाथ मिश्र ने लोकदल उम्मीदवार हुकुमदेव नारायण यादव को त्रिकोणीय संघर्ष में पौने दो लाख से भी ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। लेकिन १९८४ में सहानुभूति लहर के बावजूद हरिनाथ मिश्र दमकिपा के प्रत्याशी विजय कुमार मिश्र से बुरी तरह हार गये। विजय कुमार मिश्र स्व० ललित नारायण मिश्र के पुत्र हैं। उक्त चुनाव में उन्हें उनके चाचा डा० जगन्नाथ मिश्र का भी सक्रिय रूप से परोक्ष समर्थन प्राप्त था। चुनाव जीतने के तुरंत बाद विजय कुमार मिश्र दमकिपा छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गये थे। अब जबकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है, तो क्षेत्र की जनता के सामने यह प्रश्न खड़ा है कि इस बार किसके गले में विजय की माला पहनायी जाये? दरभंगा में बड़ी लाइन बिछवाने का वायदा भी विजय कुमार मिश्र ने अपने पिछले चुनाव में जोर-शोर से किया था। पर चुनाव जीतकर जो वे गये, तो वापस दरभंगा की तबाहियों पर उन्होंने ध्यान देना कभी जरूरी नहीं समझा। वर्षों से बंद पड़ी अशोक पेपर मिल भी आज तक नहीं खुल सकी और मिल के हजारों-हजार कामगार भुखमरी के कगार पर हैं। विजय मिश्र ने केवटी प्रखंड के पिंडारुच गांव में बागमती नदी पर पुल बनवाने का भी पिछले चुनाव में आश्वासन दिया था, पर वह भी पूरा नहीं हो सका। दरअसल चुनाव जीतने के बाद विजय मिश्र सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों में सक्रिय हो गये और सहकारिता माफिया की फेहरिस्त में उनका भी नाम चढ़ गया। सहकारिता घोटाले के सिलसिले में बिहार सरकार ने तपेश्वर सिंह आदि के साथ विजय मिश्र पर भी मामला ठोंका। लिहाजा, विजय को अग्रिम जमानत भी लेनी पड़ी। दरभंगा के मतदाता अपने सांसद की इन विवादास्पद गतिविधियों से अत्यंत आहत हैं। संसद में भी कभी दरभंगा की समस्या पर विजय नहीं बोल सके। दरभंगा में कांग्रेस आसानी से सीट निकाल सकती है, पर अपने पिटे हुए पुराने नेताओं के दम पर नहीं। दरभंगा के युवकों ने पिछले महीनों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर यह अभियान चला रखा है कि अगर कांग्रेस किसी साफ-सुथरे युवातुर्क को चुनाव मैदान में उतारती है, तो दरभंगा के नौजवान कांग्रेस प्रत्याशी को संसद में पहुंचाकर दम लेंगे। दरभंगा का बिहार के सभी संसदीय सीटों में विशेष महत्व है। राजनीतिक रूप से चेतनासंपन्न दरभंगा मिथिला का केंद्र है और पूरे बिहार में एकमात्र दरभंगा ही ऐसी जगह है जहां एक ही परिसर में दस कदम पर दो-दो विश्वविद्यालय हैं—मिथिला विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय। पर राजनीतिक दावपेंच के चक्कर में इन दोनों विश्वविद्यालयों की भी हालत खस्ता है। कालेज में शिक्षकों को यहां तनख्वाह मिले महीनों बीत जाते हैं। सत्र अनियमित है और छात्रावासों की भी बेहद दुर्गति है। लिहाजा, विश्वविद्यालयों की तबाही को दरभंगा के युवकों ने मुद्दा बना रखा है। उद्योग की शून्यता, सड़कों की बदहाली, बिजली का अभाव ये और ऐसे अनेक मुद्दे दरभंगा के मतदाताओं को आंदोलित किये हुए हैं।

माफिया की फेहरिस्त में: विजय कुमार मिश्र

फिर जनता की अदालत में: डा० सीपी ठाकुर

पटना: बिहार की राजधानी होने से पटना संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग ही महत्व है। साढ़े नौ लाख मतदातावाले इस क्षेत्र से पिछले चुनाव में इंका के डा० सीपी ठाकुर जीते थे। उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में सेना से अवकाशप्राप्त निर्दलीय उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा को भारी मतों से पराजित किया था। वैसे यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी की मानी जाती रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के रामावतार शास्त्री तीन बार यहां से सांसद हुए थे। १९७७ की जनता लहर में बिहार की संविद सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके महामाया प्रसाद सिन्हा को दो लाख वोटों से जिताकर पटना के लोगों ने लोकसभा में भेजा था।

इस क्षेत्र के मतदाताओं में कायस्थ, यादव एवं कुर्मी जाति की बहुलता है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि पटना की सत्तर प्रतिशत जनता अपने मौजूदा सांसद के कार्यकलापों से तनिक भी संतुष्ट नहीं है। विगत चुनाव के समय डा० सीपी ठाकुर ने गांधी मैदान की एक विशाल जनसभा में स्पष्ट घोषणा की थी कि लोकसभा में जाने का उन्हें अगर मौका मिलता है, तो पटना के सुंदरीकरण पर वे पूरा ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त उनके अन्य प्रमुख वादे थे—पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाना, पटना जिला स्थित मगध विश्वविद्यालय के सभी कालेजों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना, कंकड़बाग में अधूरे पड़े जयप्रभा अस्पताल का पूरी तरह निर्माण करवाकर उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल बंबई की तर्ज पर लाना, शहर की झुग्गी-झोंपड़ियों में रहनेवालों के लिए एक अलग कालोनी बसाना और पटना शहर सहित जिले के तमाम गांवों में चौबीसों घंटे बिजली व पानी की व्यवस्था करवाना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे करने की बात तो दूर रही, डा० ठाकुर क्षेत्र की जनता को कभी मुंह दिखाने भी नहीं आये। दिल्ली, सदाकत आश्रम, पटना एवं पटना के फ्रेजर रोड स्थित अपने क्लीनिकनुमा मकान तक ही डा० सीपी ठाकुर की यात्राएं होती रहीं। आम मतदाता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। अब जबकि चुनाव सामने है, डा० ठाकुर क्षेत्र की जनता से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

आईपीएफ ने अपने उम्मीदवार के रूप में बिहार सचिवालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी योगेश्वर गोप का चयन किया है। योगेश्वर गोप वर्षों से बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी गिनती जुझारू नेताओं में होती है। सरकारी सेवकों के अतिरिक्त सभी जातियों में उनकी अच्छी पैठ है। कांग्रेस को योगेश्वर गोप इस क्षेत्र से अच्छी टक्कर दे सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा कई जनसभाओं को संबोधित करने से पटना में माहौल गर्मा रहा है। बहरहाल, निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि पटना संसदीय सीट पर जोरदार लड़ाई होगी।

कुल मिलाकर, पूरे बिहार में हार-जीत किसी की हो, लेकिन चुनावी समर होगा बेहद रोमांचक। **—पटना ब्यूरो के साथ रतींद्र नाथ**

ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेन्ट केक
ज़बरदस्त झाग। किफ़ायती धुलाई।
किफ़ायती धुलाई

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा
डिटर्जेन्ट केक

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

Contract KP 96-86 HIN

आम चुनाव

सहमा बिहार !

दंगाग्रस्त भागलपुर में सेना की गश्त

सभी चौंककर रह गये थे कि एकबारगी यह क्या हो गया? पर चुनावी मौसम में ऐसे मसालेदार संगीन दृश्यों की भरमार तो राजनीतिक रजतपट पर लगी ही रहती है। मुजफ्फरपुर के कचहरी परिसर में अचानक सनसनी फैल गयी थी। यों, पहले से काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि वैशाली संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दर्ज करने मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी सिन्हा पहुंची हुई थीं, लेकिन उसी दौरान घटित उस रोमांचक प्रकरण को देखने काफी संख्या में लोगबाग उमड़ पड़े थे। यह घटना २८ अक्तूबर की है। नामांकन दर्ज कर किशोरी सिन्हा जब लोगों को संबोधित कर वहीं से अपने चुनाव-अभियान का श्रीगणेश करने जा रही थीं तभी एक सज्जन उस मौके पर वहां अवतरित हुए। ये सज्जन थे—जैतपुर स्टेट के वीरेंद्र कुमार सिह। वैशाली से किशोरी सिन्हा के मुकाबले खड़ी जनता दल की उम्मीदवार उषा सिह के पति वीरेंद्र कुमार सिह को किशोरी सिन्हा की सभा में देखकर सबको हैरानी हुई।

उषा सिह वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पारू विधानसभा क्षेत्र से जनता दल की विधायक हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णा शाही की सगी बहन उषा विगत चुनाव में विपक्ष की राजनीति में पूरे दमखम से उतरी थीं और विधायक भी चुनी गयी थी। उस चुनाव में उषा के पति वीरेंद्र कुमार सिह ने दिन-रात एककर अपनी पत्नी को विजयश्री दिलवाने में अहम भूमिका निभायी थी। उषा ने काफी पहले से मन बना रखा था कि वे इस बार संसदीय चुनाव में उतरेंगी। जनता दल ने उन्हें टिकट भी दिया, क्योंकि एक महिला के मुकाबले महिला ही कारगर उम्मीदवार हो सकती थी। पिछले संसदीय चुनाव में भी विपक्ष से खड़ी तारकेश्वरी सिन्हा ने किशोरी सिन्हा का सामना किया था। पर तारकेश्वरी क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गयीं, इसलिए विपक्ष के पास इस बार उषा सिह के अतिरिक्त कोई दूसरा अच्छा उम्मीदवार नहीं था। जहां किशोरी सिन्हा अपनी सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि के आत्मविश्वास से लैस होकर चुनावी जंग में कामयाबी हासिल करती रही हैं, वहीं बिहार राजनीति में कांग्रेस के माहिर खिलाड़ी रहे स्व० महेश प्रसाद सिंह की पुत्री होने का फायदा केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णा शाही कांग्रेस में उठाती रही हैं। उनकी अपनी बहन उषा को भी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि का लाभ विपक्ष में मिला है। इस बार संसद की चुनावी जंग की शुरुआत में ही उषा सिह अपने घर में मात खा गयीं।

दरअसल, २८ अक्तूबर को किशोरी सिन्हा की सभा में उषा के पति वीरेंद्र सिंह ने किशोरी सिन्हा के पक्ष में धुआंधार भाषण देते हुए कहा कि वैशाली की बेटी किशोरी सिन्हा को विजयी बनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। अपने पति से अनबन का खमियाजा उषा को चुनाव के मंगलाचरण में ही भुगतना पड़ा। किशोरी सिन्हा के लिए जाहिर है, चुनाव कुछ आसान हो गया, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार को मात देने के लिए उन्हें एक मजबूत मोहरा मिल गया है। जानकार बताते हैं कि वीरेंद्र को यह आश्वासन दिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें पारू क्षेत्र से कांग्रेस-टिकट दिया जायेगा, जहां से संप्रति उनकी पत्नी जनता दल की विधायक हैं।

घात-प्रतिघात : चुनाव में ऐसे हैरतअंगेज घात-प्रतिघात अस्वाभाविक नहीं। मुजफ्फरपुर में अपने प्रतिद्वंद्वी जार्ज फर्नांडिस से बेहतर शंकाकुल केंद्रीय राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ने भी जार्ज के खिलाफ शुरू में ही एक छोटा-सा पासा फेंका है। पर शाही का यह पासा किशोरी सिन्हा के पासे जैसा मारक नहीं है। ललितेश्वर शाही ने भी मुजफ्फरपुर कचहरी के प्रांगण में नामांकन दाखिल करने के पश्चात जनता दल के एक प्रमुख नेता कैप्टेन जयनारायण निषाद के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर जार्ज फर्नांडिस को झटका देने की कोशिश की। विगत संसदीय चुनाव में जार्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर क्षेत्र को छोड़ जब उत्तरी बंगलौर से लड़ने चले गये थे, तो ललितेश्वर शाही के मुकाबले में लोकदल ने कैप्टेन जयनारायण निषाद को ही लड़ाया था। निषाद ने कांग्रेस-लहर के बावजूद १,७६,६३० वोट हासिल कर ललितेश्वर शाही को कड़ा संघर्ष दिया था। मल्लाह जाति के कैप्टेन निषाद को दरकिनार कर जब जार्ज इस बार फिर अपने पुराने क्षेत्र मुजफ्फरपुर से लड़ने आ गये, तो निषाद के लिए यह असहनीय हो गया। फिर निषाद के इस

गुस्से का लाभ उठाने में ललितेश्वर शाही ने एक पल की भी देरी नहीं की। निषाद के जरिये अब शाही मुजफ्फरपुर क्षेत्र के उस पिछड़े-वर्ग के वोट में सेंध मारने की कोशिश जोरशोर से कर रहे हैं जो जार्ज का वोट-बैंक है। यों, ललितेश्वर शाही शुरू से ही जार्ज के नाम से आतंकित थे, इसलिए दिल्ली दरबार में वे टिकट वितरण के अंतिम क्षण तक गिड़गिड़ाते रहे थे कि मुजफ्फरपुर से उन्हें न लड़ाया जाये। ललितेश्वर शाही ने दिल्ली दरबार में यह मिन्नत की कि मुजफ्फरपुर के पड़ोसी क्षेत्र वैशाली से उन्हें मौका दिया जाये और वैशाली की वर्तमान सांसद किशोरी सिन्हा को उनके मुख्यमंत्री पति सत्येंद्र नारायण सिंह की सीट औरंगाबाद से लड़ा दिया जाये, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के कारण सत्येंद्र नारायण सिंह इस बार संसदीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शाही की इस मुहिम की भनक जब दिल्ली में सत्येंद्र नारायण सिंह को लगी, तो उन्होंने शाही के इस खतरनाक अभियान को खारिज करने की ठान ली। यों भी, मुख्यमंत्री से शाही के कटु संबंध हैं। मुजफ्फरपुर की राजनीति में शाही के जानी दुश्मन रघुनाथ पांडेय को सत्येंद्र नारायण सिंह ने जोर-जबरदस्ती करके अपने मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री किसलिए बनाया, यह बात किसी से छिपी नहीं। बहरहाल, झख मारकर शाही को मुजफ्फरपुर का ही रुख करना पड़ा।

किशोरी सिन्हा वैशाली में बरकरार रहीं और औरंगाबाद की अपनी सीट का उत्तराधिकार सत्येंद्र नारायण सिंह ने अपनी इकलौती पुत्रवधू श्यामा सिंह को दिलवाया। एक जमाने में 'संसद की बुलबुल' कही जानेवाली दिग्गज नेता तारकेश्वरी सिन्हा का भाग्य पता नहीं कब जगेगा। टिकट-वितरण के दौरान लगभग यह तय माना जा रहा था कि जहानाबाद या बाढ़ से तारकेश्वरी टिकट पा रही हैं। पर तारकेश्वरी टिकट से वंचित रह गयीं और ऐन चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस में शामिल हुए चरण सिंह की सरकार में परराष्ट्र मंत्री रह चुके श्यामनंदन मिश्र जहानाबाद से टिकट पा गये। बाढ़ से बिहार राजनीति के 'यादवेंद्र' रामलखन सिंह यादव को खड़ा किया गया। विगत चुनाव में रामलखन के पुत्र प्रकाशचंद्र यहां से कांग्रेस सांसद निर्वाचित हुए थे। पर अपने संसदीय जीवन में प्रकाशचंद्र ने जी भरकर 'असंसदीय कार्य' ही किये। लिहाजा, पुत्र का उत्तराधिकार इंका आलाकमान ने ऊबकर पिता रामलखन के सुपुर्द कर दिया। बिहार मंत्रिमंडल में शामिल न किये जाने से रामलखन यों भी काफी लाल-पीले हुए थे।

केसरी-केके दंगल : टिकट वितरण की तुर्शी के क्रम में दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में एक दिलचस्प शगूफा गर्म रहा कि संसद में 'जीरो आवर के हीरो' के रूप में ख्यात दूरदर्शन मंत्री केके तिवारी की इंका के वृद्ध खजांची सीताराम केसरी से जमकर हाथापायी हो गयी। इस हाथापायी में किसने-किसको पटकनी दी, इसको लेकर पटना से दिल्ली में उमड़े रसीले अफवाहबाज तरह-तरह के चोंचले लड़ा रहे थे। यों केसरी-केके दंगल की अफवाह में कितनी सचाई थी, यह कहना तो कठिन है, पर अफवाहबाज गंभीर होकर सबको यह कहते फिर रहे थे कि जब केसरी ने केके से कटाक्ष किया कि बक्सर में केके भाई इस बार कराहेंगे, तो बस 'एंग्री-यंगमैन' का भांति केके उन पर बुरी तरह टूट पड़े। दिल्ली में टिकट-मोचन यज्ञ के दौरान केके तिवारी किसी दंतकथा के नायक की भांति चर्चित रहे। प्रथम चरण में यह हल्ला जोरों से उड़ा कि केके बक्सर के बजाय इस प्रकार सहकारी माफिया तपेश्वर सिंह की सीट विक्रमगंज से लड़ाये जायेंगे और तपेश्वर का टिकट कटेगा। फिर दूसरे चरण में शगूफे में चिंगारी भड़की कि केके गोपालगंज से खड़े होंगे और इंका आलाकमान ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए विगत संसदीय चुनाव में गोपालगंज से निर्दलीय जीते काली पांडेय को इसके लिए राजी भी कर लिया है। लेकिन २५ अक्तूबर की सुबह काली पांडेय सत्येंद्र नारायण सिंह के दिल्ली स्थित आवास २८ अकबर रोड में उत्तेजित हो कह रहे थे, "अगर मेरे साथ धोखा हुआ, तो पूरे बिहार में कांग्रेस एक-एक सीट के लिए रोयेगी। टिकट मुझे मिले या नहीं, पर लड़ना तो मुझे है ही।" पर हताशा के समुंदर में गोते खा रहे काली पांडेय को आखिरकार गोपालगंज से टिकट मिल ही गया। काली पांडेय 'ताकतवर' उम्मीदवार हैं, पर पिछले चुनाव की भांति यह चुनाव उनके लिए आसान नहीं है।

काली पांडेय के टिकट पर जिस तरह संकट के बादल अंतिम क्षण तक घुमड़ते दिखायी दिये उसी तरह बलिया से पिछली बार इंका सांसद रह चुकी चंद्रभानु देवी के टिकट पर भी अंतिम क्षणों तक धुंध छायी रही। बलिया से इंका के खजांची सीताराम केसरी अपने चेले, बिहार सरकार में राज्यमंत्री, श्यामसुदंर सिंह 'धीरज' को टिकट दिलाने के लिए एकदम बेताब थे। लेकिन कटते-कटते फिर बलिया से चंद्रभानु देवी को कांग्रेस ने टिकट दे ही दिया।

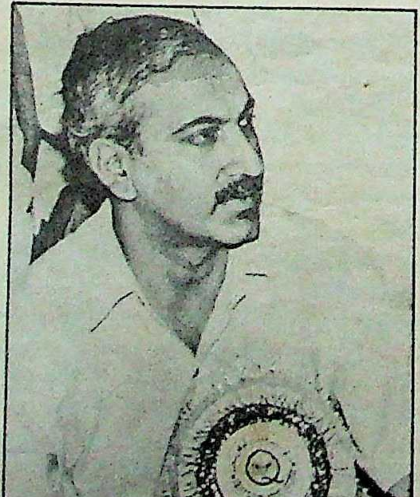

शहाबुद्दीन से मुक्ति: एमजे अकबर

विस्फोटक बयान: चंद्रभानु की भांति गौरीशंकर राजहंस भी टिकट पाने की कोशिशों में जुटे थे। पिछली बार भी जगन्नाथ मिश्र ने ही यत्न करके अपने भाई लड्डूबाबू के दामाद गौरीशंकर को संसदीय टिकट का लड्डू थमाकर जिताया भी था। झंझारपुर जगन्नाथ मिश्र का किला है, जहां के विधानसभाई क्षेत्र से वे लगातार विधायक भी होते रहे हैं। यों, सांसद होने के बाद गौरीशंकर बार-बार जगन्नाथ का पल्ला झाड़कर केंद्र में मंत्री पद के लिए जगन्नाथ-विरोधी लावी में विचरते रहे, पर जब चुनाव निकट आया, तो फिर जगन्नाथ मिश्र की गोद में 'सुरक्षित' होने का उपक्रम, वे जोरशोर से करने लगे। बीच में एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि जगन्नाथ मिश्र गौरीशंकर से अप्रसन्न हैं और इस बार वे झंझारपुर से अपनी पत्नी वीणा मिश्र को लड़ाना चाहते हैं। वीणाजी जगन्नाथ मिश्र के चर्चित 'जन विकास मंच' की कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। २३ अक्तूबर को जब दिल्ली में टिकट की लाबिंग चरम सीमा पर थी, तभी 'टाइम्स आफ इंडिया' के दिल्ली संस्करण में वीणा मिश्र का एक विस्फोटक बयान छपा। वीणा के इस बयान को लेकर दिल्ली में जमे बिहारी राजनीतिज्ञ दिल्ली दरबार के इर्दगिर्द मंडराने लगे कि जगन्नाथ मिश्र ऐन चुनाव के समय अपनी पत्नी के नाम से बयान जारी करवाकर आलाकमान को धमकी दे रहे हैं। दरअसल, वीणा मिश्र ने जन विकास मंच की ओर से नवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे को ज्ञापन देकर चेताया था कि बिहार के साथ केंद्र का अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। वीणा मिश्र ने अपने इस ज्ञापन में यह आरोप लगाया कि विकास योजनाओं और केंद्र से वित्तीय सहयोग के मामले में केंद्र बिहार के संग सदैव से भेदभाव करता आया

वैशाली के मैदान में: किशोरी सिन्हा

किशोरी सिन्हा का जवाब: उषा सिंह

है। इस ज्ञापन में बिहार की दुर्गति को आर्थिक आंकड़ों के माध्यम से साबित किया गया था। ऐन टिकट वितरण की सरगर्मी के बीच जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम से बयान का यह बम क्यों टपकाया, इसको लेकर हर बिहारी लाबी अपनी-अपनी सुविधा से व्याख्या में व्यस्त थी, पर गौरीशंकर राजहंस 'शक की सुई' से आक्रांत थे कि वीणाजी के इस बयान का सबब कहीं झंझारपुर की उनकी सीट में तो नहीं छिपा है। पर जब राजहंस टिकट पा गये, तो शक की सुई का असर खुद-ब-खुद समाप्त हो गया। झंझारपुर में जनता दल ने युवा तुर्क देवेंद्र यादव का उतारा है। पर जगन्नाथ के कवच में सुरक्षित रहने के कारण राजहंस को ज्यादा परेशानी नहीं है।

फिर मुजफ्फरपुर: जार्ज फर्नांडिस

मधुबनी से दोबारा हन्नान अंसारी को खड़ा कर कांग्रेस ने अपनी हार सुनिश्चित कर ली है। यहां से कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भोगेंद्र झा का पलड़ा बेहद भारी है। भोगेंद्र कई बार संसद में मधुबनी का प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं। हां, हन्नान की जगह किसी नये उम्मीदवार को कांग्रेस मैदान में लाती, तो भोगेंद्र झा को जीतने में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती। महाराजगंज से विपक्ष के 'महाराज' चंद्रशेखर को जनता दल ने उतारा है। चंद्रशेखर के मुकाबले कांग्रेस के कृष्णप्रताप सिंह खड़े हैं। पिछली बार भी कृष्णप्रताप यहां से सांसद चुने गये थे। कृष्णप्रताप सिंह को उनके शुभचिंतक प्यार से 'नन्हेजी' कहते हैं। और सचमुच चंद्रशेखर जैसे दिग्गज के सामने कृष्णप्रताप 'नन्हेजी' ही साबित हो रहे हैं। किशनगंज में यों नवोदित 'इंसाफ पार्टी' के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन की हालत इस बार पतली हो सकती थी, पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार और अंग्रेजी दैनिक 'टेलीग्राफ' के सम्पादक एमजे अकबर को अपना उम्मीदवार बनाकर शहाबुद्दीन की जीत को आसान बना दिया था। लेकिन किशनगंज से शहाबुद्दीन का नामंकन ही रद्द हो गया। यों, इस सीट से अकबर के नाम की अटकल काफी दिनों से चल रही थी। किशनगंज क्षेत्र के लोग गरीब हैं और अशिक्षित भी। इसलिए एमजे अकबर कितने बड़े पत्रकार हैं, यह जानने की स्थिति में किशनगंज के गरीब-अशिक्षित मतदाता नहीं है। अकबर का अंग्रेजी अखबार 'टेलीग्राफ' पढ़ने की मानसिक हैसियत किशनगंज के मतदाताओं को कभी मयस्सर ही नहीं हुई। लिहाजा, एमजे अकबर को चुनाव में एमजे अकबर होने का जो फायदा जमशेदपुर रांची सरीखे किसी विशुद्ध शहरी-औद्योगिक क्षेत्र से खड़े होने पर मिल सकता था, वह किशनगंज सरीखे बेहद पिछड़े क्षेत्र में मिलना दुर्लभ है।

टिकट कटा: रामश्रेष्ठ खिरहर

टिकट कटे: दिल्ली में सभी यह तय मानकर चल रहे थे कि तपेश्वर सिंह को इस बार संसद से संन्यास दिलाया जायेगा। स्वयं तपेश्वर सिंह भी कम सशंकित नहीं थे। पर जब कांग्रेसी प्रत्याशियों की सूची बिहार के लिए जारी हुई, तो विक्रमगंज संसदीय सीट से तपेश्वर सिंह का नाम देख सारा बिहार स्तब्ध रह गया। इसके बाद तर्क-वितर्क की जरूरत नहीं रह गयी। तपेश्वर जैसे 'महारथी' तो टिकट पा गये, पर इंका के राष्ट्रीय महासचिव रहे रामरतन राम का टिकट कट गया। सीतामढ़ी से रामश्रेष्ठ खिरहर का पत्ता साफ हो गया। रामश्रेष्ठ खिरहर का टिकट कटना पहले से तय था, क्योंकि सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की जमीन पर कब्जा कर खिरहर सीतामढ़ी की कचहरी में मुख्यमंत्री की पत्नी किशोरी सिन्हा से मुकदमा लड़ते रहे हैं। खिरहर का टिकट कटने से सीतामढ़ी में नागेंद्र यादव के भाग्य से छींका टूटा। पर सीतामढ़ी में जनता दल के दिग्गज हुकुमदेव नारायण यादव से नागेंद्र यादव की भिड़ंत मामूली नहीं है। सीतामढ़ी जिले की ही दूसरी संसदीय सीट शिवहर में केरल की राज्यपाल रामदुलारी सिन्हा के पुत्र मधुरेन्द्र सिंह का जनता दल के हरिकिशोर सिंह से कड़ा मुकाबला होगा। इस बार बिहार के कुल ५,२१,०४,६८७ मतदाताओं में ३५,४८,७१३ मतदाता १८ से २१ वर्ष की उम्र के हैं। पर न तो कांग्रेस ने और न ही जनता दल ने टिकट वितरण में युवकों को प्राथमिकता दी। लिहाजा, नाराज युवा मतदाताओं का झुकाव किस तरफ होगा, कहना मुश्किल है।

चुनावी घोषणा के साथ ही बिहार सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने लगा। भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और मोतिहारी... लगा कि पूरा बिहार मानो सांप्रदायिक जुनून में जलकर राख हो जायेगा। भागलपुर में सेना तैनात की गयी। बेहिसाब हुए कत्लेआम ने भागलपुर को तबाह कर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री भागलपुर आये। फिर गृहमंत्री बूटा सिंह व पी चिदंबरम सरीखी हस्तियां बिहार आयीं, पर जलते बिहार की आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका। खून से लथपथ भागलपुर में चुनावी झंडे लहरा रहे हैं। चुनावी दंगल में उत्तरी बिहार के बाहुबलियों की जमात को देखकर बिहारवासी रक्तरंजित मतदान होने की आशंका से भयभीत हैं। बिहार में चुनावी मंगलाचरण दंगे से हुआ है, उम्मीद करनी चाहिए कि प्रशासन चुनावों का समापन रक्तपात से नहीं होने देगा।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

◆ लोग ◆

महेंद्र मोहन गुप्ता

दैनिक जागरण, कानपुर के निदेशक महेंद्र मोहन गुप्ता इस बार यानी १९८९-९० के लिए इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी के अध्यक्ष चुने गये हैं। वे आईएनएस के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश से इस पद के लिए चुना गया है। परिश्रमी और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी श्री गुप्ता से सोसायटी को काफी अपेक्षाएं हैं।

सोवियत पत्रिकाएं
त्यौहार के
मौके पर
विशेष छूट

सोवियत संघ

सचित्र मासिक पत्रिका

नये जीवन का निर्झर

विश्व की बीस भाषाओं में प्रकाशित यह पत्रिका अपने पाठकों को सोवियत जीवन के सभी पहलुओं से, सोवियत जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी और काम से परिचित कराती है ।

सोवियत पुरुषों और महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं तथा क्रियाकलापों में नये खुलेपन के वातावरण को प्रतिबिम्बित करती है ।

12 अंक मुफ्त 33% बचत कीजिए

विशेष छूट का लाभ उठाइये
तीन वर्ष के लिए चंदा भेजिए
और 33% की बचत कीजिए
12 अंक मुफ्त
रियायत साल के आखिर तक उपलब्ध

"सोवियत संघ" के लिए डी डी/एम ओ प्रेषित है
तीन वर्ष का चन्दा 60 रुपये
एक वर्ष का चन्दा 30 रुपये
(अवाछनीय काट दीजिये)

नाम ____________________

पता ____________________

____

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
५-ई रानी झांसी रोड
नई दिल्ली-११००५५

राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.) लि
चमेलीवाला मार्किट,
एम आई रोड, जयपुर-३०२००१

मैगज़ीन सेन्टर
एम सी डी बिल्डिंग
न. २, दूसरी मंजिल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
[illegible]-११००५५

मनीषा ग्रन्थालय (प्रा.) लि.
४/३. बी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-७०००७३

26

क्या चुनाव इतिहास को दुहरायेगा ?

लगभग १२ वर्षों बाद आंध्र प्रदेश देश में चुनावी महाभारत का सर्वाधिक कौतूहल का केंद्र बन गया है। राज्यसत्ता (तेलुगूदेशम) और केंद्रीय सत्ता (कांग्रेस-इ) की तमाम व्यूह-रचनाओं और दावों-दबावों के बावजूद्र सचाई यह है कि दोनों पक्ष दिवास्वप्न के मारे हैं, क्योंकि दोनों के लिए मतदाताओं का मन जान पाना मुश्किल हो गया है। न कोई लहर है, न किसी के प्रति सहानुभूति, न ही कोई दमदार मुद्दा और मतदाता हैं कि दोनों पक्षों को गिरगिट की तरह रंग बदलते नजर आ रहे हैं। नवंबर, १९८९ का चुनाव इस गर्म और गीली जलवायुवाले प्रदेश का आठवां अनुभव है, जबकि छह साल की क्षेत्रीय तेलुगूदेशम पार्टी तीन (एक लोकसभा, दो विधानसभा) चुनावों में सौ साल की अखिल भारतीय कांग्रेस को धूल चटाने के बाद चौथी बार लामबंद हो रही है। इस एकसदनी (विधान परिषद १९८५ में भंग कर दी गयी) राज्य के चुनावी महाभारत में इस बार भी पिछले प्रतिद्वंद्वी ही युद्ध संचालक हैं—एक ओर हैं, तेलुगूदेशम अध्यक्ष व मौजूदा मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामाराव जो राष्ट्रीय मोरचे के भी प्रमुख हैं, तो दूसरी ओर राज्य इंकाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री एम चेन्नारेड्डी तथा कांग्रेस प्रमुख प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो क्या आंध्र प्रदेश पिछले इतिहास को दुहरायेगा? या रामाराव और उनकी पार्टी की कमजोरियों का लाभ कांग्रेस पा जायेगी? मुसीबत यह है कि राज्य के तीनों भागों—तटवर्ती आंध्र, भीतरी रायलसीमा और तेलंगाना—का एक चक्कर लगाया जाये, तो भी इन प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता। क्यों? "क्योंकि तेलुगूदेशम अब भी ऊपर उठती हुई पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस दरबारियों और फिरकापरस्तों की पार्टी बनकर रह गयी है जो तेलुगूदेशम का विकल्प बन ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर तेलुगूदेशम से ज्यादा भ्रष्ट और बदनाम हो चुकी है।" यह जवाब है एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जिन्होंने नाम न छापने के आग्रह पर जुबान खोली।

ऐतिहासिक भिड़ंत: फिर भी चुनाव को लेकर गजब की गहमागहमी है। सिर्फ हैदराबाद को देखकर कहा जा सकता है कि तेलुगूदेशम और कांग्रेस-इ दोनों तरफ से पूरा महाभारत लड़ने की तैयारी है। ऐतिहासिक भिड़ंत है। हार-जीत का फैसला करनेवाले हैं ४,२५,४२, ४५० मतदाता जिनमें २९,३९,०७५ युवा हैं, यानी १८-२१ वर्ष की वयवाले, जिनमें अपना भविष्य खुद बनाने की लगन है।

वास्तव में इतनी जल्दी चुनाव के लिए न तो सत्तापक्ष तेलुगूदेशम तैयार था, न प्रतिपक्ष कांग्रेस-इ। खासकर मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के लिए तो यह ऐलान एक अप्रत्याशित हमला ही था। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के अनुरोध के साथ केंद्र को पत्र भेजकर पहले उन्होंने ही चौंकाया था। शायद उन्होंने यह उम्मीद कर रखी थी कि चुनाव जनवरी में होंगे और दस राज्यों में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभाओं के चुनाव कराये जायेंगे। शायद उनका इरादा भ्रांति फैलाकर कांग्रेस का मनोबल गिराना भी रहा। लेकिन चुनाव के आकस्मिक निर्णय और विधानसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश के चयन ने रामाराव को समझा दिया कि चुनाव के संचालन और निर्देशन में उन्हें अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह मानना कि राजीव गांधी भी आंध्र प्रदेश के लिए अपेक्षित समय नहीं दे पायेंगे, सिर्फ अपने आपको तसल्ली देनी है।

रामाराव राष्ट्र-स्तरीय महत्वाकांक्षा को तभी तक तरजीह देंगे, जब तक उन्हें विश्वास रहेगा कि उनका राज्य का आधार बरकरार है।

रामाराव की विडंबना: यकबयक दोहरे चुनाव की घोषणा रामाराव के लिए कितनी भारी पड़ रही है, इसके दो स्पष्ट प्रमाण हैं। एक, यह कि शुद्ध चुनाव-प्रचार के उद्देश्य से जिस फिल्म 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' को बनाने में वे चार महीनों से रात-दिन लगे थे, उसका निर्माण स्थगित करना पड़ा और दूसरा यह कि केंद्र की ओर रुख रहने के बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव न लड़ने को बाध्य होना पड़ा। वास्तव में प्रत्याशियों के चयन और चुनाव की मोरचेबंदी की दिशा में रामाराव ने अभी कुछ किया ही नहीं था। तेलुगूदेशम के मित्र दलों, खासकर माकपा और जनता दल से सीटों का तालमेल भी नहीं हो पाया था। चुनाव की पृष्ठभूमि बनाने के लिए विकास और जनहित की कोई फौरी योजना भी वे नहीं तय कर पाये थे। यह सब रामाराव 'विश्वामित्र' बन जाने के बाद करनेवाले थे। अब यह काम ज्यादा कठिन हो गया। यकायक ३३६ (४२ लोकसभा, २९४ विधानसभा की) सीटों के बंटवारे की उलझन आ पड़ी। जिलेवार विधायकों-सांसदों से बातचीत की प्रक्रिया अपनाते, तो इतने कम समय में अपने सहयोगी दलों और तेलुगूदेशम के असंतुष्ट नेताओं को खुश रखते हुए शायद ही वे सफल हो पाते। ५० फीसदी टिकट युवा और नये चेहरों को देने के रामाराव के वायदे से यह मसला और उलझ गया। रामाराव पिछड़े कापू समुदाय को यथेष्ट टिकट देकर खुश रखने की जरूरत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण इस समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए कांग्रेस-इ और बहुजन समाज पार्टी आकाश-पाताल एक किये हुई थीं। ये सारे मसले रामाराव को जल्दी में तय करने पड़े हैं।

२१ अक्तूबर को गंडीपेट स्थित तेलुगूदेशम पार्टी के मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मोरचे के अध्यक्ष एनटी रामाराव ने लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करते हुए कहा था, "मूलतः मैं तेलुगू संस्कारोंवाला आदमी हूं, इसलिए मैं राज्य को छोड़ना नहीं चाहता। दिल्ली दरबार की सत्ता की लिप्सा मुझमें नहीं है।" इस घोषणा ने राज्य ही नहीं, बल्कि देश को भी चौंका दिया। दो साल पहले जब रामाराव विपक्षी दलों को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने में सक्रिय हुए, तब से अब तक वे लोकसभा चुनाव लड़ने की पृष्ठभूमि बनाते रहे। सच तो यह है कि वे प्रधानमंत्री पद के सपने संजोनेवाले विपक्षी महारथियों में रहे। हैदराबाद में यह चर्चा बराबर गर्म रही कि रामाराव ने आनंदपुर जिले की आनंदपुर या हिंदूपुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है।

रामाराव के गृह-क्षेत्र कृष्णा जिले के लोग वहीं (कृष्णा) से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए दबाव डाल रहे थे, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बना रहे। पिछले दिसंबर में इंका विधायक वीएम रंगाराव की हत्या के बाद सबसे अधिक कृष्णा जिला ही हिंसा, आगजनी और लूट का शिकार हुआ था। कापू समुदाय (जिसके सदस्य रंगाराव थे) और अन्य वर्गों को पहुंची क्षति की भरपाई के लिए रामाराव के दामाद डाक्टर डी वेंकटेश्वर राव तथा उनके साथियों ने बहुत प्रयास किया था। १९८३ और १९८५ में रामाराव ने कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा जिले से चुनाव जीता था। इसीलिए उनके समर्थकों की राय रही कि रामाराव इस बार भी विधानसभा चुनाव गुडीवाड़ा से और लोकसभा चुनाव मछली पत्तनम से ही लड़ें।

नया युद्ध, पुरानी रणनीति: हैदराबाद के राजनीतिक पर्यवेक्षक रामाराव के लोकसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान को सही मानते हैं। रामाराव राष्ट्र-स्तरीय महत्वाकांक्षा को तभी तक तरजीह देंगे, जब तक उन्हें विश्वास रहेगा कि उनका राज्य का आधार बरकरार है। लोकसभा

चुनावों के बाद राष्ट्रीय मोरचे (जिसके वे अध्यक्ष हैं) का सत्ता-समीकरण क्या बनेगा, यह निश्चित नहीं है। पर राज्य में उनकी सत्ता बनी रहेगी, यह प्रायः निश्चित है, इसलिए निश्चित को दांव पर लगाकर अनिश्चित के लिए दौड़ पड़ना रामाराव ने अनुचित माना।

राज्य में इस बार भी सीधा मुकाबला है। एक ओर हैं, तेलुगूदेशम और उसके सहयोगी दल, दूसरी ओर कांग्रेस-इ। राज्य में सत्तारूढ़ होने के नाते तेलुगूदेशम ने विपक्ष का वोट न बटने देने और गैरइंका पार्टियों में एका कायम रखने के लिए भाजपा, माकपा और जपा के साथ १९८५ का तालमेल प्रायः बनाये रखा है। भाकपा भी १९८५ में उसकी सहयोगी रही, लेकिन बाद में उससे अलग हो गयी। रामाराव ने उससे भी पुराना रिश्ता बनाये रखने में सफलता पा ली है। हैदराबाद के राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि मित्र दलों के साथ तेलुगूदेशम का सीटों के साथ तालमेल कुछ बदला है, लेकिन रणनीति वही है जो '८५ में थी।

यदि भाकपा तेलुगूदेशम से समझौते तोड़े रह जाती, तो रामाराव की मुश्किल बढ़ जाती, क्योंकि करीब ७० विधानसभा क्षेत्रों में वह ५००० से १०,००० तक वोट काट सकती थी। इसका लाभ कांग्रेस-इ को मिलता, क्योंकि ८५ के चुनावों मे अधिकतर क्षेत्रों में वह ५००० वोटों से ही हारी थी। हैदराबाद के राजनीतिक गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि औपचारिक समझौता न होने पर भी गैरकांग्रेस दलों में टकराव नहीं होगा। माकपा ने इसके लिए एक योजना सुझायी है, जिसके तहत तेलुगूदेशम लोकसभा की चार सीटें (दो माकपा, दो भाकपा के लिए) और विधानसभा की ३५ सीटें छोड़े हुई है। माकपा की योजना भाकपा और तेलुगूदेशम दोनों के लिए फायद्देमंद है। लेकिन इससे कांग्रेस-इ का गणित उलट गया है।

> **भले मजलिस हैदराबाद के बाहर न जीते, लेकिन वोट काटकर गैर-इंका उम्मीदवारों को लाभ तो पहुंचा ही सकती है।**

मजलिस का रुख : कांग्रेस-इ के लिए दूसरा आघात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (मिम) और तेलुगूदेशम के बीच छिपे तौर पर हो रही साठगांठ बतायी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस-इ और मजलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर सहयोग होता रहा है। दरअसल हैदराबाद नगर निगम पर मजलिस की मौजूदा हुकूमत कांग्रेस-इ के सहयोग की ही देन है। इंका, मजलिस से जबानी तालमेल ही बैठा सकती थी, विधिवत गठबंधन से उस पर सांप्रदायिक पार्टी से हाथ मिलाने का आरोप लग सकता था। उधर चर्चा है कि तेलुगूदेशम ने मजलिस को अधिक-से-अधिक शहरी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि कांग्रेस की जीत की संभावना कम-से-कम रह जाये। इंका का मानना था कि यदि मजलिस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आते, तो अल्पसंख्यकों के वोट कांग्रेस-इ को ही मिलते। हैदराबाद के सांसद और मिम प्रमुख सुलतान सलाउद्दीन ओवैसी अपने तुरुप के पत्ते को लेकर बहुत चौकस हैं। चूंकि तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों के कई जिला मुख्यालयों और कस्बों में १५ से २० प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं, इसलिए कांग्रेस-इ और तेलुगूदेशम दोनों का संतुलन मजलिस बना-बिगाड़ सकती है। ओवैसी ने साफ कह दिया है कि ५ लोकसभा सीटों और ५० विधानसभा सीटों पर मजलिस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भले मजलिस हैदराबाद के बाहर न जीते, लेकिन वोट काटकर गैर-इंका उम्मीदवारों को लाभ तो पहुंचा ही सकती है। पिछले चुनाव में राजधानी हैदराबाद की लोकसभा सीट और ५ विधानसभा सीटें जीतकर मजलिस अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि बन गयी थी। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में उसने गैरमुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े किये थे।

दूसरी ओर कांग्रेस-इ को कई तेलुगूदेशम विरोधी गुटों—मसलन निवासुल रेड्डी की सेन्नैया सेना, नादेंडला भास्कर राव के लोकतांत्रिक तेलुगूदेशम, मुद्रागदा पद्मनाभम तथा केई कृष्णमूर्ति के तेलुगूनाडु—ने अपने विलय से कांग्रेस-इ का हौसला बढ़ाया है। लेकिन इस विलय से चुनाव पर विशेष प्रभाव पड़ने के आसार नजर नहीं आते।

अपनी-अपनी हुज्जत : कुछ नक्सली गुट चुनाव लड़ने पर आमादा हैं, तो कुछ ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों के अपने-अपने अंतर्विरोध हैं, अपनी-अपनी हुज्जतें हैं। कोई छह महीने पहले तेलुगूदेशम में अपूर्व विप्लव फट पड़ा था। ६० विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला दिया। बड़ी आपाधापी के बाद सुलह-सफाई हुई, तिस पर भी छह विधायक पार्टी छोड़ ही गये। तब से रामाराव के मन में अपने विधायकों और पूर्व मंत्रियों की निष्ठा पर संदेह पैदा हो गया है। इनमें से अधिकांश तो इस बार टिकट पाने से रह गये हैं। एक का कहना है, "५० फीसदी नये चेहरे लाने के वायदे का यही सबब है।" शायद इसी कारण विधानसभा अध्यक्ष जी नारायण राव ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या इन वंचित-विशुब्धों की भूमिका का असर नहीं होगा तेलुगूदेशम की चुनाव संभावनाओं पर?

उधर कांग्रेस-इ का एक खासा तबका प्रदेश इंका प्रमुख चेन्ना रेड्डी की खुली खिलाफत कर रहा है। मुद्दा है, पार्टी में चिर उपेक्षित पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का। हालांकि असंतुष्टों ने चुनाव के मद्देनजर यह खिलाफत बंद करने का वचन दिया है, पर इसका मतलब यही है कि खिलाफत अब भूमिगत होकर चलेगी। टिकट न मिलने के कारण जो क्षोभ पैदा हुआ है, वह भी पार्टी को नुकसान पहुंचायेगा। पार्टी के हिंसक और हमलावर तत्वों ने मतदाताओं को अपनी हरकतों से नाराज कर रखा है। ऐसे तत्व तेलुगूदेशम में भी हैं, लेकिन वे जवाबी कार्रवाईवाले लोग हैं।

१९८३ और '८५ के विधानसभा चुनावों, १९८५ के लोकसभा चुनावों और ८७-८८ के स्थानीय निकाय चुनावों (देखें बाक्स) के नतीजे बताते हैं कि तेलुगूदेशम का संगठन, आधार और नेतृत्व तीनों काफी मजबूत हैं। राज्य की अग्रणी विपक्षी पार्टी कांग्रेस-इ की क्षमता और संभावना भी बढ़ती गयी है। यह स्थानीय निकायों के चुनावों तथा रामाराव सरकार के खिलाफ उसके हाल के राज्यव्यापी प्रदर्शनों से स्पष्ट हो गया है। हिंसा का जवाब हिंसा से देना तो उसने दिसंबर १९८८ में अपने विधायक वीएम रंगाराव की हत्या के तुरंत बाद शुरू कर दिया है। वह तेलुगूदेशम को सत्ता से बेदखल करने के लिए सब तरह से तैयार है। पार्टी के सर्वोच्च नेता राजीव गांधी हाल के महीनों में तीन यात्राओं में राज्य के छह जिलों का दौरा कर चुके हैं और अब चुनाव के दौरे भी करेंगे। जवाब में विपक्ष के महारथी भी आयेंगे।

मतदाता की नजर : दोनों पक्षों में किसी के पास वोटबटोरू मुद्दा नहीं है। तेलुगूदेशम द्वारा जारी पंफलेट और घोषणा-पत्र से साफ है कि वह बोफोर्स दलाली, अन्य घोटालों, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को लेकर हो-हल्ला मचायेगा। कांग्रेस के पास भी वही घिसी-पिटी बातें हैं—एनटीआर की कथित कारगुजारियां, भाई-भतीजावाद, एनटीआर के दामादों की दखलंदाजियां, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचार, नक्सली हिंसा में इजाफा, कानून व्यवस्था की बदहाली आदि।

बहरहाल, दोनों पक्षों की ओर से लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए युद्ध शुरू हो गया है। इंका के रणबांकुरों में हैं, केंद्रीय मंत्री जे वेंगलराव, पी शिवशंकर, पीवी नरसिम्हाराव, विधानसभा में विपक्ष के नेता बग्गा रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय भास्कर वगैरह-वगैरह। तेलुगूदेशम का मोरचा संभाल रहे हैं, पी उपेंद्र, चंद्राबाबू नायडू, पूर्व मंत्री के शिवप्रसाद राव, विधिमंत्री आनंद राव, गृहमंत्री माधव रेड्डी। बिगुल बज चुका है। दोनो तरफ के भोंपू तेज हो गये हैं। पोस्टर-बैनरों, वीडियो-प्रदर्शनों, सभाओं-भाषणों और जुलूसों का बाजार क्रमशः गरमाता जा रहा है। लेकिन मतदाता की निगाह कहां है, कोई नहीं जानता।

नामजदगी के दौरान एक खास बात यह रही कि तेलुगूदेशमवालों का विशेष चाव विधानसभा के लिए था, तो कांग्रेसियों का लोकसभा के लिए। यह एक संकेत हो सकता है, पर निर्णायक तथ्य नहीं।

—वशिष्ठ

अमेठी

क्या चुनौती नाम मात्र है ?

राजीव गांधी

राजमोहन गांधी

अपनी जीत सुनिश्चित मानकर अमेठी की सीट से लड़ रहे राजीव गांधी के लिए इस बार लोकसभा पहुंचना पहले जैसा आसान नहीं होगा। हालांकि दो बार इस सीट से जीत चुके राजीव गांधी के पक्ष में तमाम बातें और कारण गिनवाये जा सकते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में राज मोहन गांधी और काशीराम के चुनावी मैदान में उतरने से लगने लगा है कि इस बार अमेठी में 'लड़ाई' भयंकर होगी।

वर्ष १९८१ और १९८४ में इस क्षेत्र से जब राजीव गांधी भारी बहुमत से जीते थे, तो उनके मुकाबले में क्रमश: शरद यादव और मेनका गांधी उम्मीदवार थीं। दूसरी बार चुनाव जीतने पर राजीव गांधी का ऐसा जनाधार बना था कि अमेठी क्षेत्र में विपक्ष की हालत पतली हो गयी थी। लंबे अरसे तक यहां विपक्षियों के चेहरों पर मायूसी झलकती रही, पर अब, जबकि देश-प्रदेश के अन्य हिस्सों में विपक्षियों के हौसले बुलंद हुए हैं, अमेठी में भी मायूस चेहरों पर रौनक नजर आने लगी है। यही कारण है कि चुनावी तैयारियों के तहत विपक्षी कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर तोड़ने का कार्य इस क्षेत्र में काफी तेजी से शुरू हो चुका है। पिछले चुनाव में मेनका गांधी के पक्ष में लड़ने-जूझने वाले अनेक स्थानीय नेता—कार्यकर्ता सत्तादल के वाहनों पर सवार हो चुके हैं।

इसके विपरीत महात्मा गांधी के पौत्र होने के कारण राज मोहन गांधी के प्रति क्षेत्रवासियों का आकर्षण अपनी जगह कायम है। राज मोहन गांधी विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं। जाहिर है, विपक्ष के दिग्गज उनके लिए अमेठी में घूमेंगे। उन्हें जनता दल का चुनाव चिह्न भी मिला हुआ है। किंतु विधानसभाई सीटों पर जनता दल और भाजपा के बीच तालमेल न हो पाने से यह सवाल अहम हो गया है कि विधानसभा चुनाव में एक-दूसरे के विरुद्ध तलवार भांजते भाजपा और जद के उक्त उम्मीदवार, संसदीय सीट पर साझा उम्मीदवार के लिए किस प्रकार काम करेंगे ?

वैसे, राज मोहन गांधी के पास वक्त भी बहुत कम है। लगभग दो सप्ताह के अल्प समय में उन्हें पांच विधानसभाई क्षेत्रों का दौरा, कार्यकर्ताओं से संपर्क और साधनों के इंतजाम से लेकर 'विपक्षी वोटों को बचाने' तक का कठिन कार्य पूरा करना है, क्योंकि वोटों की लूट और मतदान स्थल पर कब्जे के लिए अमेठी की शोहरत कम नहीं है !

ऐसी स्थिति में जानकारों का कहना है, "१९७७ जैसे माहौल मे तो जनता की मदद से विपक्ष जूझ सकता है, पर अन्य स्थितियों में राजीव गांधी बनाम राज मोहन गांधी की लड़ाई केवल 'प्रतीकात्मक' ही हो सकती है।" पर्यवेक्षकों का मानना है कि अमेठी, गौरीगंज और तिलोई में विपक्ष की स्थिति पहले से काफी मजबूत हुई है जबकि सलोन और जगदीशपुर में विपक्ष के घुटने कमजोर हैं।

हरिजन नेता कांशीराम की ताकत को सिर्फ 'वोट काटने तक ही सीमित समझा जा रहा है। पर वे स्वयं इसे मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है, "मैं जीतने के लिए ही अमेठी से खड़ा हुआ हूं।" लेकिन उनका स्वयं का और उनकी पार्टी का चुनावी रिकार्ड, उन्हें 'वोट काटने' वाली ताकत से अधिक नहीं बताता। जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो बेशक कांशीराम की स्थिति राज मोहन गांधी से बेहतर है। उनका संगठनात्मक ढांचा अमेठी में मजबूत नहीं, तो कमजोर भी नहीं है। लेकिन वास्तव में उनकी पहुंच 'हरिजन वर्ग' तक ही सीमित है। 'वर्ग विशेष' की ताकत के बूते अच्छा चुनाव तो लड़ा जा सकता है, पर यह ताकत विजय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि कांशीराम की अमेठी में मौजूदगी जहां कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनेगी, वहीं राज मोहन गांधी के लिए हितकर साबित होगी। क्योंकि वे हरिजनों के जिन मतों को खींचेंगे, वह कांग्रेस के परंपरागत मत समझे जाते हैं।

चुनावी राजनीति के क्षितिज पर अमेठी के बाद दूसरा नाम उभरता है, फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का। यहां वर्तमान इंका सांसद एवं केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री हरीकृष्ण शास्त्री और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच सीधी टक्कर है। जहां क्षेत्र में औद्योगिक विकास के बूते हरीकृष्ण शास्त्री को अपनी जीत की उम्मीद है, वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ठाकुर बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट को अपने लिए सर्वाधिक सुरक्षित समझा है।

फतेहपुर संसदीय क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में बांदा जिले का तिन्दुवारी क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष १९७८ के उप चुनाव में इंका हाई कमान ने वीपी सिंह के कहने पर ही फतेहपुर संसदीय सीट में ठाकुर बहुल तिन्दवारी विधानसभा सीट को जोड़ा था। लेकिन इस वक्त इस संसदीय सीट की केवल बिन्दकी विधानसभा सीट जनता दल के अचल सिंह के कब्जे में है। बाकी चारों सीटों में तिन्दुवारी से अर्जुन सिंह, फतेहपुर से खान गुफरान जाहिदी, हसवा से अमरनाथ तथा (सुरक्षित) किशनपुर से इंद्रजीत इंका के लिए काबिज हैं। इस तरह जातिगत समीकरण के मुताबिक, फतेहपुर संसदीय क्षेत्र में तीन विधानसभाई सीटों पर ठाकुर, एक पर मुसलमान तथा एक पर हरिजन विधायक हैं।

चुनावी समीकरण यदि वीपी सिंह के पक्ष को मजबूत करते दिखायी पड़ते हैं, तो हरीकृष्ण शास्त्री की स्थिति को भी नाजुक नहीं कहा जा सकता। क्षेत्र के प्रभावशाली ठाकुरों की आपसी टकराहट शास्त्री के पक्ष में जा सकती है। १८ प्रतिशत ठाकुरों के मुकाबले १६ प्रतिशत ब्राह्मणों का वोट बैंक भी उनकी हालत सुदृढ करता है। दूसरी ओर यहां के आम मतदाताओं से लेकर गांव के छुटभैया नेताओं तक विश्वनाथ प्रताप सिंह को बहुत करीब से जानते हैं। वीपी सिंह इसी सीट से १९७८ में अपने भाई सतंबक्स सिंह को चुनाव जिता चुके हैं।

इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल यह बता पाना मुश्किल है कि किसकी झोली भरेगी और कौन हाथ मलेगा ?

—लखनऊ ब्यूरो

आम चुनाव

कांग्रेसी फौज में दहशत

यद्यपि उम्मीदवारों के चयन में प्रदेश इंका अध्यक्ष बलराम सिंह यादव और राष्ट्रीय महामंत्री गुलाब नबी आजाद सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने चहेतों को टिकट दिलवा लिया है, लेकिन उन्हें जिताने की सारी जिम्मेदारी अब नारायण दत्त तिवारी कें सर है। ऐसे कई अच्छी छवि वाले वर्तमान विधायकों, जिनके टिकट कट गये हैं, के बारे में पूछे जाने पर तिवारी कहते हैं, "मुझे स्वयं दुख है कि इनके टिकट काटे गये। हरदेव (रसड़ा-बलिया) का टिकट तो कल्पनाथ राय ने ही कटवाया है। मैंने अपनी ओर से हर 'नेता' के उम्मीदवार को 'एडजस्ट' करने की पूरी कोशिश की है।"

बागी पंत : केंद्रीय रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत के प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि टिकटों के बंटवारे में तिवारी के आगे किसी की नहीं चल सकी। चुनाव की घोषणा के पहले से ही केसी पंत यह प्रयास कर रहे थे कि उन्हें नैनीताल की संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया जाये। इसी

क्रम में पिछले छह माह के दौरान पूरे कुमायूं मण्डल में पंत ने तिवारी विरोधियों की लामबंदी शुरू कर दी थी। चूंकि तिवारी उन्हें पहाड़ में वापस घुसने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नैनीताल से लगे बरेली जिले की आंवला संसदीय सीट से पंत की उम्मीदवारी का यह कहते हुए संसदीय बोर्ड में समर्थन किया कि इस सीट से पंत को जिताने में वे पूरी मदद करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर पत ने आंवला और नयी दिल्ली दोनों में से किसी क्षेत्र से न लड़ने की घोषणा और नारायण दत्त तिवारी की व्यक्तिगत आलोचना कर यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि नैनीताल से उनका टिकट कटवाने में तिवारी की ही चाल है।

पंत द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के बारे में तिवारी कहते हैं, "प्रदेश की राजनीति में मेरी कोई जमींदारी या एकाधिकार नहीं है। मुझे स्वयं इस बात का आश्चर्य है कि पंत जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा मुझ पर ऐसा आरोप लगाने के पीछे उनका मंशा क्या है।"

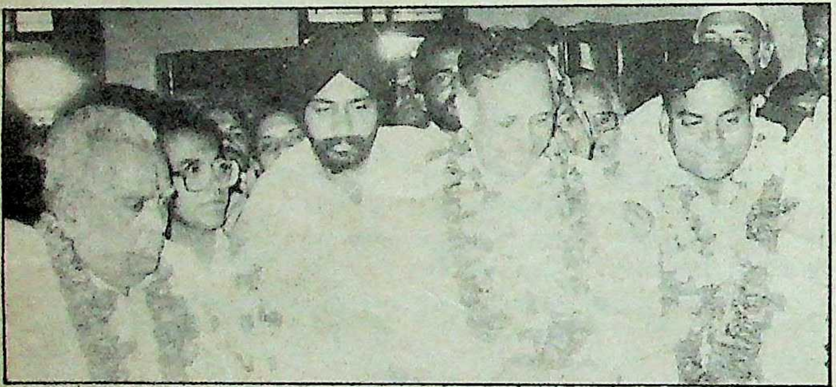
कर्मचारी नेता की स्थिति मजबूत : नामांकन करते हुए दाऊजी गुप्त (कांग्रेस) तथा मांधाता सिंह (जद)

लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टिकट बंटवारे में सारा फायदा तिवारी को ही हुआ हो। उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इटावा में श्रीमती सुखदा मिश्रा को दुबारा टिकट न दिया जाना तथा विपक्ष छोड़कर कांग्रेस में आये सत्यदेव त्रिपाठी (इटावा) और सुभाष त्रिपाठी (सुलतानपुर) की उपेक्षा से भी इन जिलों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गयी है। सुखदा मिश्रा ने जहां इटावा में विपक्ष का बिगुल बजा दिया है वहीं सीतापुर में अपनी उपेक्षा से दुखी राम कुमार भार्गव ने पार्टी से विद्रोह कर जनता दल की उम्मीदवारी हासिल कर ली है।

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ हो रहे हैं। यही वजह है कि हाई कमान ने चुनाव में हार-जीत की पूरी जिम्मेदारी नारायण दत्त तिवारी पर सौंपकर उन्हें चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है।

तिवारी की भूमिका : टिकट के बंटवारे में 'सिटिंग' (वर्तमान) को 'रिपीट' करने का जो सिद्धांत उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, उससे न केवल खराब छवि के लोग पुनः टिकट पाने में सफल हुए हैं, वरन् कई ऐसे बहुचर्चित चेहरे जिनके टिकट १९८५ में काट दिये गये थे, उन्हें पुनः मैदान में उतार दिया गया है।

भ्रष्टाचार के पर्याय बने स्वास्थ्य मंत्री गोपीनाथ दीक्षित, ग्राम विकासमंत्री श्याम सूरत उपाध्याय, सार्वजनिक निर्माणमंत्री अम्मार रिजवी, लघु उद्योगमंत्री बेनी बाई और नियोजनमंत्री रघुवीर सिंह यादव जैसे लोग कांग्रेस की ओर से पुनः मैदान में उतारे गये हैं, वहीं पद्मा सेठ (बिलवां-सीतापुर), विनोद चौधरी (महोना-लखनऊ), कु० कृष्णा रावत (मलिहाबाद-लखनऊ), बच्चा पाठक (बांसडीह-बलिया), भोला पांडे (द्वाबा-बलिया), शंभू नाथ सिंह (आजमगढ़) तथा आगरा के गुलाब सेहरा आजाद कुमार कर्दम, महेश उपाध्याय को टिकट मिल जाने से इन क्षेत्रों के इंकाइयों में व्यापक असंतोष है।

इस बार कांग्रेस ने गढ़वाल से संसद के लिए सतपाल महाराज जैसे प्रवचन देने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बाल्टी बाबा के नाम से विख्यात जगदीश प्रसाद मिश्र को कसया (देवरिया) से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है।

विजय बहुगुणा खफा : श्रीमती कमला बहुगुणा के साथ इंका में वापस आनेवाले तमाम लोगों में से जहां राम निहोर राकेश (चायल-इलाहाबाद) और राम लाल राही (मिश्रिख-सीतापुर) को और स्वयं श्रीमती बहुगुणा को संसद का टिकट दे दिया गया, वहीं उनके पुत्र विजय बहुगुणा सहित सभी समर्थकों की खुलकर उपेक्षा की गयी।

जिलों में पहले से चली आ रही गुटबंदी और उपेक्षा के विरुद्ध विद्रोह की सुगबुगाहट चुनाव से पूर्व ही मुखर हो उठी है। जहां संयुक्त विपक्ष से कांग्रेस का साबका है, वहीं कुछ को छोड़कर अन्य जगहों पर कांग्रेस स्वयं शोचनीय स्थिति में है। जैसे लखनऊ में तिवारी ने दाऊजी गुप्त को मैदान में उतार दिया है, लेकिन राज्य कर्मचारी-शिखर नेता मान्धाता सिंह और भाजपा के राम प्रकाश गुप्त (पूर्व उप मुख्यमंत्री) के भी मैदान में होने से कांग्रेस के लिए यह सीट निकाल पाना मुश्किल माना जा रहा है। उन्नाव में बांगरमऊ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री गोपी नाथ दीक्षित और संसदीय सीट के उम्मीदवार केंद्रीयमंत्री जियाउर्रहमान अंसारी के गुटों की लड़ाई अब सड़क पर आ गयी है। जियाउर्रहमान पर लगे बलात्कार के आरोप के प्रकरण को इसी नजरिये से देखा जा सकता है। दोनों गुट एक दूसरे को हराने में कमर कसे हैं। इसी तरह सीतापुर में अम्मार रिजवी और राजा महमूदाबाद अमीर मोहम्मद खां की आपसी लड़ाई ने पूरे जिले की कांग्रेसी राजनीति को कसैला बना दिया है। इस लड़ाई और बिसवां से राम कुमार भार्गव को टिकट न मिलने से उपजे विद्रोह ने यहां से संसद की उम्मीदवार राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को सांसत में डाल दिया है।

मोहसिना की उलझन : मेरठ में मोहसिना किदवई जिले की गुटबाजी में उलझी हुई हैं। जहां राज्यसभा सदस्य शांति त्यागी समर्थक श्रीमती किदवई को हराने में जुटे हैं, वहीं मंजूर अहमद जैसे सशक्त उम्मीदवार के उनके विरोध में (निर्दलीयं) आ जाने से यहां का मुकाबला कांटे का हो गया है। बदायूं संसदीय सीट के वर्तमान सांसद सलीम शेरवानी को एटा से १९८४ में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले महफूज अली खां उर्फ प्यारे मियां के खिलाफ मैदान में उतारा गया है, तो बदायूं में राम नरेश यादव का जनता दल के सशक्त नेता शरद यादव से सामना कराया जा रहा है। विपक्ष की परंपरागत संसदीय सीट बाग़पत से अजीत सिंह के विरुद्ध कांग्रेस ने दुबारा महेश चंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है। १९८४ की लहर के बावजूद महेश चंद्र शर्मा चौधरी चरण सिंह के इस गढ़ में सेंध नहीं मार पाये थे, इस बार तो हवा का रुख ही बदला हुआ है। पीलीभीत संसदीय सीट से इंका के वर्तमान सांसद भानु प्रताप सिंह का मुकाबला इस बार विपक्ष की संयुक्त प्रत्याशी मेनका गांधी से है। कांग्रेस पहले यहां से मेनका के खिलाफ अकबर अहमद डंपी को खड़ा करना चाहती थी, इसीलिए भानुप्रताप सिंह को भोजीपुरा (बरेली) से विधानसभा का टिकट दे दिया गया था, लेकिन अकबर अहमद द्वारा मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार करने और कोई दूसरा सशक्त प्रत्याशी न मिलने पर, मजबूर होकर कांग्रेस ने पुनः भानु प्रताप सिंह को मेनका के मुकाबले खड़ा कर दिया। सिखबहुल तराई वाले इस क्षेत्र में मेनका का पलड़ा सिख मतों के कारण भारी है।

कुल मिलाकर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि कांग्रेस-इ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है, उनमें कुछ गिने-चुने दिग्गजों को छोड़कर लगभग सभी खौफ और दहशत के साये में चुनावी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। —लखनऊ ब्यूरो

ी) के भी
ट निकाल
उन्नाव में
रहे प्रदेश
र संसदीय
ाउर्रहमान
र आ गयी
के आरोप
सकता है।
र कसे हैं।
और राजा
ी आपसी
ानीति को
बिसवां से
ी से उपजे
ार राजेंद्र
दिया है।
मोहसिना
ई हैं। जहां
क श्रीमती
ूर अहमद
विरोध में
बला कांटे
के वर्तमान
१९८४ में
न अली खां
तारा गया
नता दल के
कराया जा
दीय सीट
ने दुबारा
है। १९८४
धरी चरण
, इस बार
पीलीभीत
भानु प्रताप
की संयुक्त
हले यहां से
ी को खड़ा
प सिंह को
ा टिकट दे
ारा मेनका
कार करने
मिलने पर,
प सिंह को
सिखबहुल
सिख मतों

दा उचित
विधानसभा
ा है, उनमें
ाभग सभी
मुहिम को
नऊ ब्यूरो

जो सुरक्षा रेमण्ड सीमेंट से मिले वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले.

इसलिए चाहे आपका अपना घर हो या दफ़्तर या फिर कोई अन्य निर्माण कार्य, भरोसा कीजिए केवल रेमण्ड सीमेंट पर. क्योंकि रेमण्ड सीमेंट ठोस हैं इसके फ़ायदे : उत्तम दबाव शक्ति (कम्प्रैसिव स्ट्रैंथ), जमाव का बढ़िया मानक, मज़बूत पैकिंग.

जी हां, रेमण्ड सीमेंट को बरसात, धूप और समय जैसी कुदरत की फौलादी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है.

याद रखिए, रेमण्ड सीमेंट के कण-कण में भरी है सर्वोत्तम सुरक्षा और सर्वोत्तम शक्ति.

R
कैलाश ब्रांड
रेमण्ड सीमेंट
१०० साल वाला सीमेंट

विश्वामित्र

एनटीआर का दूरदर्शनी जवाब

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटीआर की निर्माणाधीन फिल्म 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' क्या आम चुनाव में कांग्रेस-इ के लिए घातक सिद्ध होती? अन्यथा सरकारी संरक्षण में दक्षिण के जाने-माने फिल्म निर्माता दसरि नारायण राव द्वारा इसी विषय पर टीवी सीरियल बनवाकर गुपचुप उसका प्रसारण प्रारंभ कर देने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी?

एनटीआर से मुकाबला : विश्वामित्र के एक दृश्य में मुकेश खन्ना और सुरेंद्र पाल

८ अक्तूबर को 'महाभारत' के बाद बिना किसी पूर्व-घोषणा या प्रायोजकों के प्रचार-अभियान के दक्षिण सिनेमा के जादूगर माने जानेवाले दसरि नारायण राव के विवादास्पद सीरियल 'विश्वामित्र' का प्रसारण शुरू हुआ, तो लोगों का चौंकना स्वाभाविक ही था। एक बार तो 'महाभारत' के दोनों बहुचर्चित कलाकारों (भीष्म: मुकेश खन्ना तथा द्रोणाचार्य: सुरेंद्र पाल) के चेहरे देखकर लोगों को लगा कि कहीं दूरदर्शन द्वारा 'महाभारत' के सेंसरित अंश तो गलती से नहीं दिखलाये जा रहे हैं।

"दरअसल 'महाभारत' के बाद लोग आम तौर पर टीवी बंद कर देते हैं" 'विश्वामित्र' के पिता राजा गाधि की भूमिका निभा रहे सुरेन्द्र पाल ने 'माया' को बतलाया, "इसीलिए बहुत से लोग इसे नहीं देख पाये। कुछ लोगों ने कुछ देर बाद टीवी खोला, तो उन्हें मेरा और मुकेश खन्ना का चेहरा दिखलाई पड़ा। उन्हें गलतफहमी हो गयी, क्योंकि सेट तथा कास्ट्यूम भी महाभारत काल जैसे ही थे।"

लेकिन सबसे अधिक भौचक्के हुए नंदमूरि तारक राव उर्फ एनटीआर। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' ऐन दीवाली के दिन समूचे भारत में रिलीज हो जायेगा और चुनाव तक जोर पकड़ लेगा। लेकिन दशहरे से ठीक दो दिन पहले 'विश्वामित्र' को प्रसारित कर देने की सूचना राज्य प्रसारण मंत्री केके तिवारी अपनी विजय मानते हैं, क्योंकि एनटीआर का खुफिया तंत्र अपने ही राज्य की राजधानी हैदराबाद में बन रही दसरि नारायण राव की 'विश्वामित्र' की प्रगति की सही रिपोर्ट उन्हें नहीं मुहैया करा सका और वे मुगालते में रहे। उधर मंडी हाउस तथा केके टीवी (केके तिवारी ब्राडकास्ट) के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली दूरदर्शन ने 'विश्वामित्र' को ८ अक्तूबर को ही प्रसारित कर उन्हें मात दे दी। साथ ही केकेटीवी ने दसरि नारायण राव की इस 'सहायता' के लिए अचानक शिड्यूल में परिवर्तन कर 'विश्वामित्र' के प्रसारण के दूसरे ही रविवार १५ अक्तूबर को, उनकी 'फिल्म 'प्यासा सावन' दूरदर्शन पर प्रसारित कर उन्हें 'उपकृत' भी कर दिया।

सहायता और सहयोग से इनकार: जब एनटीआर ने 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' की शूटिंग शुरू की थी, तो आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने दसरि नारायण राव को एनटीआर के मुकाबलेवाली 'विश्वामित्र' बनाने के लिए हर तरह के 'सहयोग' और 'सहायता' का आश्वासन दिया था। लेकिन दसरि नारायण इस तरह की किसी भी 'सहायता' और 'सहयोग' की बात से इनकार करते हैं। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "मैं 'विश्वामित्र' पर एक भव्य फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन इतने विशद विषय को ढाई घंटे की फिल्म में निबटा देना आसान काम नहीं था, बल्कि उनके चरित्र के साथ एक तरह का अन्याय भी होता, इसलिए 'विश्वामित्र' पर टीवी सीरियल बनाने की मैंने बहुत पहले योजना बनायी थी, इस पर काफी काम भी किया था, लेकिन कार्य रूप में उसकी परिणति इस समय हुई, जब समूचे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एनटीआर से मेरी प्रतिद्वंद्विता जरूर रही है, लेकिन घटिया स्तर पर नहीं।"

अभिनेता सुरेंद्र पाल 'माया' को बतलाते हैं, "वे सही कहते हैं। चोपड़ा साहब (बीआर चोपड़ा) की ही तरह उन्होंने भी इसे (विश्वामित्र) पूरी भव्यता से बनाया है। कास्ट्यूम से लेकर सेट-निर्माण तक में कहीं भी कोताही नहीं बरती है, न ही किसी तरह का समझौता किया है। इसे आप पूरी निष्ठा से बनाया गया एक महंगा टीवी सीरियल कह सकते हैं।"

सुरेंद्र पाल की बात की ताईद 'विश्वामित्र' की भूमिका निभा रहे मुकेश खन्ना भी करते हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, "'महाभारत' में भीष्म की केंद्रीय तथा 'गौतम बुद्ध' (ब्रेकफास्ट सीरियल) में बुद्ध की भूमिका निभाने के बाद 'विश्वामित्र' में नायक की भूमिका निभाना और बीआर चोपड़ा जैसे महारथी के साथ लंबे अरसे तक काम करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मेरे लिए। एनटीआर तेलुगू भाषा के जाने-माने वयोवृद्ध अभिनेता हैं। उन्होंने 'विश्वामित्र' की भूमिका निश्चय ही बहुत प्रभावशाली ढंग से निभायी होगी, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि इसे और भी प्रभावशाली ढंग से निभाऊं। मैं अपनी

तुलना उनसे तो नहीं करता, लेकिन 'विश्वामित्र' की भूमिका निभाना उस समय जरूर बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, जब ठीक वही भूमिका एक बहुत बड़ा महारथी-अभिनेता भी निभा रहा हो। यह गलत बात है कि दसरि नारायण राव ने 'विश्वामित्र' को जल्दबाजी या आनन-फानन में बनाया और मंडी हाउस तथा कांग्रेस पार्टी से जा-बेजा समझौते किये। मैं उनकी कार्यशैली और फिल्मांकन-क्षमता से सचमुच चमत्कृत रह गया था।''

दसरि नारायणं राव ने 'विश्वामित्र' में अधिकतर कलाकार 'महाभारत' तथा 'रामायण' से लिये हैं। इसकी पटकथा-संवाद डा० राही मासूम रजा ने लिखे हैं तथा संगीत की धुनें राजकमल की हैं। ये दोनों 'महाभारत' से जुड़े हैं। इसी तरह मुकेश खन्ना (भीष्म) और सुरेंद्र पाल (द्रोणाचार्य) के अलावा और भी कई कलाकार तथा तकनीशियन 'महाभारत' के हैं। इसी तरह 'रामायण' के राम (अरुण गोविल), सीता (दीपिका) तथा रावण (अरविंद त्रिवेदी) को क्रमश: सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती तथा त्रिशंकु की भूमिकाओं के लिए चुना गया है। पहले राजा गाधि की भूमिका अभिताभ बच्चन तथा मेनका का किरदार श्रीदेवी निभानेवाली थीं, लेकिन 'डेट्स' की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण दसरि नारायण राव ने सुरेंद्र पाल को लेकर शूटिंग शुरू कर दी, क्योंकि वे शूटिंग रोकने के लिए तैयार नहीं थे। मेनका की भूमिका अभी भी वे श्रीदेवी अथवा रूपा गांगुली (द्रौपदी) से करवाना चाहते हैं। सोनम भी इस भूमिका को करना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ समस्या है कि वे ग्लैमरस तो हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में पारंगत नहीं और दसरि नारायण राव के पास उनके नृत्य में पारंगत होने तक की प्रतीक्षा के लिए समय नहीं, इसलिए उन्होंने तेलुगू की एक अभिनेत्री को लेने का निश्चय किया, उसका स्क्रीन टेस्ट भी वे ले चुके हैं। यों भी विश्वरत की पत्नी माधवी की भूमिका दक्षिण की खूबसूरत अभिनेत्री संध्या ने निभायी है। मेनका की बात पर वे मुस्कराते हैं, ''मैं लोगों (उनका इशारा एनटी रामाराव के मुहूर्त-समारोह की तरफ था) की तरह ढोल बजा, हंगामे कर तथा भारी-प्रचारबाजी कर कोई काम नहीं शुरू करता। आप मेनका के लिए इतने उतावले क्यों हैं ? जल्द ही उसे भी आप टीवी के परदे पर देख लेंगे। या जल्द ही उसके बारे में भी आपको बतला दूंगा।''

कांग्रेस-इ को क्या लाभ: टीवी सीरियल विश्वामित्र में संध्या और सुरेंद्र पाल

मंडी हाउस पर आरोप: केकेटीवी उर्फ मंडी हाउस पर लोगों का आरोप है कि उन्होंने एनटीआर के 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' तथा चुनाव से पहले इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने की जल्दबाजी में अपने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। नियमानुसार न तो उन्होंने इसका पायलट स्वीकृत करने के लिए मांगा और न ही पांच एपीसोड जमा करने पर टाइम स्लाट देने के नियम का ही निर्वाह किया। यह ठीक है कि दसरि नारायण राव ने सारा काम आनन-फानन में नहीं निबटाया, लेकिन मंडी हाउस ने 'विश्वामित्र' का कैसेट मिलते ही तुरत-फुरत, बिना किसी पूर्व घोषणा के ही, इसे ८ अक्तूबर को प्रसारित कर दिया। बंबई दूरदर्शन के एक अधिकारी का कहना था, ''सारा कुछ आनन-फानन में इस तरह हुआ कि हमें भी नियमानुसार निर्धारित समय पर शिड्यूलिंग के पूर्व सूचना नहीं मिल सकी। जैसे उन्हें पता था कि नवंबर के तीसरे या अंतिम सप्ताह में चुनाव होनेवाले हैं। शायद उन्होंने सोचा हो कि तब तक सात-आठ एपीसोड टेलीकास्ट हो चुके होंगे। ऐसे में विश्वामित्र की कथा उजागर हो जाने के कारण एनटीआर का 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' प्रभावहीन साबित हो जाये।''

कथा: लोकतंत्र में आस्था रखनेवाले महाराजा गाधि (सुरेंद्र पाल) का बेटा विश्वरत (मुकेश खन्ना) स्वभाव में एकदम उलटा था। वह अहंकार को राजा का सबसे बड़ा अलंकरण मानता था। एकछत्र सम्राट बनने लिए उसने दूसरे राजाओं पर आक्रमण कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की ललक में सत्य-असत्य का विवेक ही खो दिया था। अविवेक के इन्हीं क्षणों में उसकी राज्य एवं शक्ति-लोलुप निगाह महर्षि वशिष्ठ की दैवीय शक्तिशाली गाय नंदिनी पर आ टिकी और उसने आश्रम पर हमला कर दिया, परास्त होने पर उसने एक के बाद कई दुरूह तपस्याएं कीं। यहीं से उसकी महर्षि वशिष्ठ से एक लंबे टकराव की शुरुआत हुई। राजपाट त्याग कर तपस्या करने का उसका उद्देश्य भी सिर्फ शक्ति अर्जन करना था। इसी दौरान सशरीर स्वर्गारोहण की आकांक्षा लिये अयोध्या के महाराजा सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ से मिले और अनुरोध किया। जब वशिष्ठ ने उनकी न सुनी तब उनसे निराश हो कर वे विश्वरत के पास आये। वशिष्ठ पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का सही मौका देखकर उन्होंने उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने की बात मान ली और तपस्या शुरू कर दी, जिसे इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेज कर भंग करा दिया, फलत: सत्यव्रत त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटके रह गये, तो विश्वरत ने तपस्या-शक्ति से उनके लिए एक नये स्वर्ग का निर्माण कर दिया।

महर्षि वशिष्ठ से खुद को 'ब्रह्मर्षि' की उपाधि पाने में असफल विश्वरत ने क्रोध में उनके एक पुत्र को छोड़कर शेष दस पुत्रों की हत्या करा दी। लेकिन जब वशिष्ठ ने कहा कि 'तुम चाहो, तो इस अंतिम पुत्र की भी हत्या कर दो, लेकिन ब्रह्मर्षि का पद नहीं पा सकते। निराश-अहंकार शून्य विश्वरत वापस लौटने को हुआ, तो अपने लिए वशिष्ठ से 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' संबोधन सुनकर चौंका और इसका राज पूछा, तो उन्होंने कहा, ''इस समय न तो तुममें अहंकार शेष रह गया है और न ही कोई लिप्सा। इसलिए तुम 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' के नाम से न केवल तीनों लोकों में लोकप्रिय होगे, बल्कि बहुत सारे महान कार्य करोगे।'' और वशिष्ठ की इस बात तथा उपदेश ने अहंकारी विश्वरत का कायाकल्प कर दिया।

'महाभारत' सीरियल की जहां से शुरुआत होती है, वहीं 'विश्वामित्र' का समापन होता है। इसमें वैदिक मंत्रों की रचना से लेकर राम-कथा के कतिपय प्रसंग तथा राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र-मेनका के संसर्ग से उत्पन्न शकुंतला तथा उनके पुत्र भरत की कथा भी है। मंडी हाउस ने अभी तो सिर्फ १५ एपीसोड मंजूर किये हैं, लेकिन इसे २६ एपीसोड तक कर दिये जाने की पूरी संभावना है।

—बंबई ब्यूरो

जीवन के रंग अजीब...

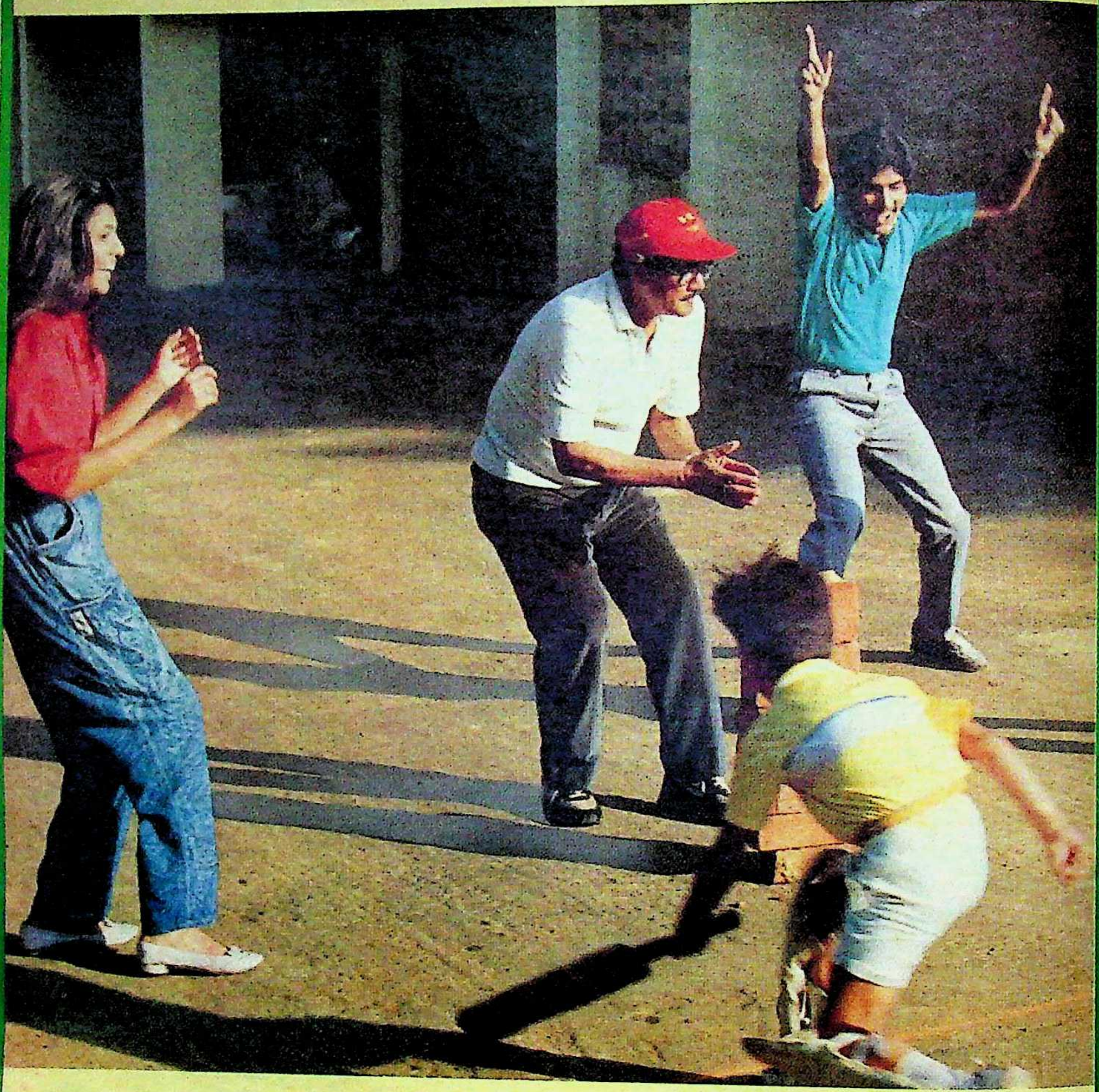

शुक्र है बोरोलीन करीब

ख़ुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

BOROLINE
REGD. TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

सूखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

Response 1039

गुटबाजी से त्रस्त: मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर

आम चुनाव

गुटों में बंटा पक्ष-विपक्ष

विजय की उम्मीद: जब नेता नाथूराम मिर्धा

दिनांक: १६ अक्तूबर। स्थान: जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय। विषय: नौवीं लोकसभा के लिए राजस्थान के इंका प्रत्याशियों का चयन। दिल्ली से लौटकर प्रदेश मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा द्वारा गठित ग्यारह सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक में चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संभावित इंका प्रत्याशियों के नामों के पैनल पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, तो सांसद अशोक गहलोत ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राम किशन दीक्षित का नाम पैनल में रखने का सुझाव दिया, तभी प्रदेश कांग्रेस-इ कोषाध्यक्ष एवं विधानसभा में चुरू जिले का प्रतिनिधित्व करनेवाले चंदनमल बैद ने टिप्पणी की, "अरे! यह तो सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत पाये।" इस पर गहलोत का कहना था कि चुरू के उपचुनाव के समय वर्तमान सांसद नरेंद्र बुढानिया के साथ दीक्षित के नाम पर भी विचार किया गया था, अत: पूर्व के समान इस बार भी उनका नाम पैनल में शामिल करना वाजिब होगा। जब बहस कुछ गर्म हुई, तो मुख्यमंत्री माथुर और बैद ने जोर देकर कहा कि विचार उन्हीं नामों पर किया जाना चाहिए जिनमें सांसद बनने की कूवत हो। इसका जवाब दिया प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रघु शर्मा ने, "जब एमएलए का चुनाव हारनेवाले एमपी का टिकट बांट सकते हैं, तो सरपंच का चुनाव हारनेवाले एमपी का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता।" रघु शर्मा की इस टिप्पणी पर बैद, मदेरणा व दूलाराम भड़क उठे। ऐसे में रघु शर्मा का पक्ष लेते हुए सेवादल के अध्यक्ष महेश जोशी, कांग्रेस-इ के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर खान, कांग्रेस-इ के वरिष्ठ कांग्रेसियों से भिड़ गये। प्रदेश कोषाध्यक्ष बैद ने अब देवपुरा से कहा, "मैं तो पहले ही कह रहा था कि इनकी बात सुनकर इन्हें विदा कर देना चाहिए था।"

गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस: इसी नोक-झोंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आस्कर फर्नांडीस का एक पत्र बैठक में पेश हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष को युवा कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआर सहित प्रदेश के चारों अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों को चुनाव समिति का सदस्य बनाने के निर्देश थे। विवाद और तूल पकड़ता, इसके पूर्व ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राजस्थान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव दिलीप सिंह भूरिया का प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष के नाम जो फोन आया, उसने न केवल इस बैठक को अर्थहीन बना दिया, बल्कि उस समिति को ही ध्वस्त कर दिया जो लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों का चयन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष देवपुरा और मुख्यमंत्री माथुर ने इस दावे के साथ बनायी थी कि इसे श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने तय किया है और इस पर आलाकमान की स्वीकृति की मोहर लग चुकी है। लेकिन भूरिया ने प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष को फोन पर स्पष्ट हिदायत दी कि वह जिस कमेटी को चुनाव समिति करार दे रहे हैं, वह आलाकमान द्वारा अधिकृत नहीं है। लोकसभा चुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी निभानेवाली कमेटी में पुत्रमोह के तहत दल से घात करनेवाले जोधपुर संभाग के कांग्रेसी नेता परसराम मदेरणा, वरिष्ठता के आधार पर पदचाह करनेवाले चंदनमल बैद को व 'बिगड़ी छवि' के पर्यायवाची बने अनुसूचित जाति के दूलाराम को शामिल करने से अशोक गहलोत व अन्य युवा नेता बेहद नाराज थे, क्योंकि ये वे लोग थे जो युवाओं को आगे लाने के घोर विरोधी थे। दूलाराम ने तो बाकायदा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर गहलोत और उनके समर्थकों को अरुण नेहरू का दलाल बताया था। लेकिन भूरिया के फोन पर दिये गये निर्देश के कारण चुनाव कमेटी से परसराम मदेरणा, दूलाराम और चंदनमल बैद के नाम हटा दिये गये। आलाकमान ने ११ की जगह १८ सदस्यों की चुनाव समिति तय कर २० अक्तूबर को उसकी बैठक दिल्ली में आयोजित करने के आदेश जारी कर दिये। ऐसे ही परस्पर अविश्वास के माहौल में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया।

नयी कमेटी में सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री राजेश पायलट, बिहार के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की सांसद पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शीशराम ओला व श्रीमती कमला भील, सांसद भुवनेश चतुर्वेदी व प्रदेश कांग्रेस-इ के महामंत्री हनुमान प्रभाकर को शामिल किया गया। इनके अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस के चारों अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों यानी रघु शर्मा, महेश जोशी, जुबेर खान व श्रीमती कांता कथूरिया का नाम जोड़ा गया। दिल्ली में बड़े स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवपुरा और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने चुनाव समिति के नामों की सूची आलाकमान को भेजकर उसे अधिकृत सूची का नाम देने की जालसाजी की थी।

आखिर माथुर और देवपुरा को ऐसी जालसाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल, इन दोनों को अंदाज नहीं था कि इतनी जल्दी आमचुनाव की घोषणा हो जायेगी। मुख्यमंत्री माथुर धार्मिक यात्रा पर तिरुपति गये हुए थे, तो देवपुरा केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह के चुनाव क्षेत्र भरतपुर का जायजा ले रहे थे।

१७ अक्तूबर को दोनों नेताओं को जब चुनाव घोषणा का पता चला, तो देवपुरा उसी रात दिल्ली चले गये और माथुर दूसरे दिन मद्रास से दिल्ली पहुंच गये। प्रदेश कांग्रेस-इ पहले ही इस कदर गुटों में बंटी रही है कि हरिदेव जोशी का कद कम करने के लिए कभी शिवचरण माथुर और गहलोत एक हो गये थे, तो अब अशोक गहलोत को हाशिये पर पटक देने के लिए देवपुरा और माथुर एक हो गये थे और दोनों चाहते थे कि प्रत्याशियों के चयन में उनके लोगों को तरजीह मिले।

गहलोत गुट को निष्प्रभावी बनाने के लिए देवपुरा व माथुर ने चुनाव समिति गठित कर जो कोशिश की थी, उसे आलाकमान ने नयी समिति गठित कर नाकाम कर दिया। इस प्रकार राजस्थान में इंका प्रत्याशी कांग्रेस-इ के प्रंदेश संगठन के जिस रथ पर चढ़कर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उसके सारथी तो देवपुरा और माथुर नजर आते हैं, लेकिन घोड़ों की लगाम किन्हीं अदृश्य हाथों में हैं। समझा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार से उन लोगों की छंटनी कर दी जायेगी जो राजसुख का उपभोग करते हुए बदनाम हो गये हैं—लेकिन यह तभी संभव है, जब कांग्रेस-इ एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाये।

भाजपा सकते में नहीं: पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की २५ सीटों में से १५ पर भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। उनका मानना है कि प्रदेश की राष्ट्रवादी ताकतें उन्हें इस बार लोकसभा में भारी तादाद में भेजेंगी। चुनाव घोषणा के दौरान भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें शिरकत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा तथा विशेष आमंत्रित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी दिल्ली जा चुके थे।

चुनाव मुद्दा अगर रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तक सीमित रह गया, तो विजय उसी की होगी, जिसे धर्माचार्य या मुल्ला मौलवी चाहेंगे।

कांग्रेस-इ के समान ही प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने के लिए भाजपा की भी चुनाव समिति गठित हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश चुनाव समिति में युवाओं, महिलाओं और पिछले वर्गों के प्रमुख नेताओं को शामिल नही किया गया है। जब कार्यकर्ताओं का रोष उग्र होने लगा, तो चुनाव समिति में फेरबदल कर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछली समिति के छह सदस्यों को हटा दिया। तब कहीं जाकर राजस्थान के भाजपा प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जा सका।

जनतादल: नाथूराम मिर्धा व कल्याण सिह कालवी तथा मोहन प्रकाश और मोहन छगानी के गुटों में बंटे जनतादल ने भी गुटबाजी पर ध्यान न देते हुए आम चुनाव के लिए कमर कस ली है। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा प्रदेश के सांप्रदायिक दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हुए, उससे किसी भी गठबंधन से इनकार करते रहे हैं। पर लोकसभा की चुनाव घोषणा ने स्थितियां बदल दी हैं। 'राजीव हटाओ' के एक सूत्री कार्यक्रम के तहत भाजपा एवं विपक्ष के नेता भैरोंसिह शेखावत, जद के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा, विधायक मोहन छंगाणी सीटों के बंटवारे की जोखिम भरी प्रक्रिया में व्यस्त हो गये।

राजाओं की वफादारियां: आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस-इ के टिकट से जिला प्रमुख निर्वाचित हुए भरतपुर के पूर्व महाराजा बृजेंद्र सिंह के इकलौते पुत्र विश्वेंद्र सिंह ने पाला बदलकर भरतपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पिछले पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने विश्वेंद्र सिंह को जिला प्रमुख का कांग्रेस टिकट दिलवाया था। समझा जा रहा था कि मुख्यमंत्री भरतपुर राजघराने से अपने संबंध बनाकर मानसिह हत्याकांड से अपने को बरी करने की चेष्टा कर रहे हैं। हालांकि, इस प्रयास से विदेश राज्यमंत्री नटवर सिह खुश नहीं थे, लेकिन गुटबाजी के लिए मशहूर कांग्रेस का तत्कालीन माथुर-पायलट गठबंधन नटवर सिह को राजस्थान की राजनीति में अपने आश्रित रखने के लिए यह खेल खेल गया। कल तक राजीव गांधी की प्रशंसा में अखबारों में विज्ञापन छपवानेवाले विश्वेंद्र सिंह अब कहते हैं कि एक दिसंबर, १९८८ को मुख्यमंत्री को अपने सगाई समारोह में बुलाकर उन्होंने एक राजनीतिक भूल की थी। अब उनका कहना है कि दरअसल, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने राजघराने में फूट डालने के लिए कुचक्र रचकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहा था। निश्चित रूप से केंद्रीय विदेशराज्य मंत्री नटवर सिंह के इस रिश्तेदार के जनता दल का उम्मीदवार बनाये जाने से नटवर सिंह का भरतपुर से विजयी होना पहले जैसा सहज नहीं रह गया था—संभवतः इसी कारण उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने वहां से हटाकर उत्तर प्रदेश की मथुरा संसदीय सीट का टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस-इ समर्थन में अपील जारी करनेवाले उदयपुर के पूर्व विवादास्पद महाराणा महेंद्र सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। उनका मुकाबला इंका प्रत्याशी व मौजूदा सांसद श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत से होगा।

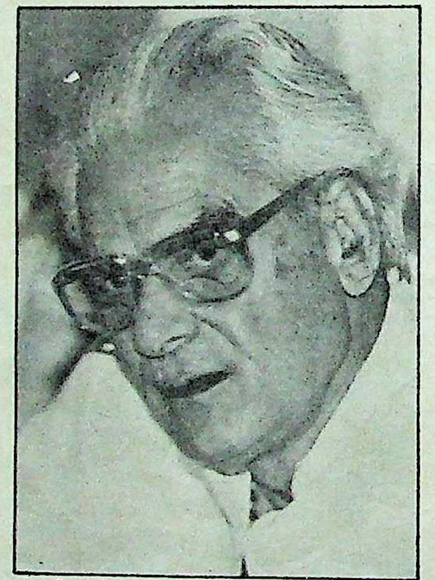

राम शिला के भरोसे: भाजपा नेता भैरोंसिह शेखावत

भाजपा से तालमेल: कल्याण सिह कालवी

राजाओं की वापसी के इस दौर में भीलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले बनेड़ा ठिकाने के राणा हेमेंद्र सिंह भी भाजपा उम्मीदवार बने हैं। सन १९७१ में वे जनसंघ के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। आपातकाल में कांग्रेस-इ के साथ रहते हुए फिलवक्त बनेड़ा पंचायत के सरपंच हैं। हेमेंद्र सिंह ने २३ अक्तूबर को भाजपा में शामिल होने की घोषणा उदयपुर के पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह की उपस्थिति में की। इस घोषणा से भीलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इंका प्रत्याशी के लिए कड़े मुकाबले की स्थितियां बन गयी हैं।

महिलाएं और युवक: राजस्थान से पहली बार लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व सन १९६२ के आम चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर

मुद्दा रामजन्मभूमि : गुमानमल लोढ़ा

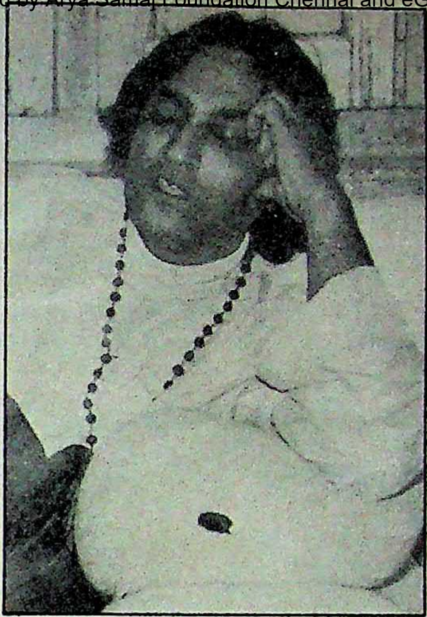

हिंदू वोट बैंक का सपना : आचार्य धर्मेंद्र

विजयी होकर जयपुर की राजमाता गायत्री देवी ने किया था। १९६७ में भी वे राजस्थान से एकमात्र महिला प्रतिनिधि थीं। १९७१ में इसमें इजाफा हुआ और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के साथ-साथ जोधपुर की राजमाता कृष्णा कुमारी निर्दलीय के रूप में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं।

दिलचस्प तथ्य यह है कि जनता लहर के दौरान एक भी महिला को राजस्थान से लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, यानी १९७७ के आम-चुनाव में विपक्ष की लहर के बावजूद महिलाओं को नजर-अंदाज किया गया। वैसे, प्रगतिशील होने का दावा करनेवाली कांग्रेस जयपुर में राजमाता के सामने महिला उम्मीदवार खड़ी करती रही है, लेकिन महिला उम्मीदवार को विजयी बनाकर १९८० में पहली बार वह चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भेज पाने में सफल रही। उक्त चुनाव श्रीमती निर्मला कुमारी सिंह ने जीता था। पिछले आम चुनावों में उदयपुर से कांग्रेस-इ टिकट पर श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया और चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती निर्मला कुमारी विजयी रही थीं यानी विपक्ष से लोकसभा में केवल राजमाताएं पहुंचती रही हैं, तो कांग्रेस-इ से प्रभावी राजनेताओं की पत्नियों को ही लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला है।

युवाओं को लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कराने में जनसंघ, जनता व भाजपा प्रमुख रहे हैं। सन १९७१ में भारतीय जनसंघ ने २५ वर्षीय हेमेंद्र सिंह को भीलवाड़ा से लोकसभा के लिए निर्वाचित किया था। १९७७ में यह गौरव जनता दल के जनसंघ घटक के नाथू सिंह को हासिल हुआ। सन १९८० में जोधपुर से अशोक गहलोत को कांग्रेस-इ के टिकट पर युवा प्रतिनिधित्व मिला। १९८४ में अजमेर और जोधपुर से एक बार फिर युवा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, पर कुलमिलाकर पक्ष-विपक्ष का युवा व महिला प्रतिनिधित्व लोकसभा में राजस्थान से नाममात्र के लिए रहा है। इस बार देखना है कि कांग्रेस-इ और विपक्षी दल कितने युवाओं और महिलाओं को लोकसभा में भेजने में सफल हो पाते हैं।

चुनाव मुद्दे क्या हैं ? : दलाली, भ्रष्टाचार और महंगाई, जहां प्रदेश में विपक्षी दलों के नारे बने हुए हैं, वहीं कांग्रेस विपक्ष को जन-विरोधी करार देने के लिए राज्यसभा में पंचायती राज तथा नगरपालिका विधेयकों की पराजय की कथा कह रही है। बहरहाल, दोनों पक्षों के केंद्र से प्रचारित ये नारे जनमानस की जुबान पर नहीं चढ़े हैं। हां, राजस्थान में रामशिला पूजन और बाबरी मस्जिद का सवाल शहरों, कस्बों और गांवों में प्रवेश करता जा रहा है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक—इन सवालों को लेकर आमने-सामने हैं। रामशिला पूजन एवं श्रीराम महायज्ञ समिति के प्रदेश अध्यक्ष व राजस्थान एवं गोहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढा न्याय की सारी सीढ़ियां उतरकर अब केवल हिंदू मतों की चर्चा में लगे हैं।

राजस्थान बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य धर्मेंद्र को राज्य सरकार ने उत्तेजना व घृणा फैलानेवाले भाषण देने के आरोप में आठ अक्तूबर को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया था। आचार्य ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था। आचार्य की सहानुभूति में उनके शिष्यों ने कई कस्बों में बंद का आयोजन किया। नतीजा यह हुआ कि आचार्य को २२ अक्तूबर को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। राजस्थान में भाजपा विधायक हरीश शर्मा को शिवसेना का संयोजक बनाया गया है। हिंदू राष्ट्र निर्माण के इनके खयालात भी जयपुर, जोधपुर और कोटा में काफी प्रभाव पैदा कर रहे हैं।

ठीक इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लीगी नेता कोटा, बांरा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली में अपना असर दिखा रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की इंसाफ पार्टी ने नौ सितंबर को जोधपुर शहर में अपनी प्रादेशिक शाखा शुरू की थी, इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय की शिरकत गौरतलब थी। जहां राम जन्मभूमि के समर्थक प्रदेश के विभिन्न संभागों से राम शिलाओं को रथनुमा ट्रकों में सजाकर जयपुर लाकर अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, वहीं बाबरी मस्जिद के हिफाजती दस्तों के अल्पसंख्यक समर्थक हिंदू संगठनों के इस प्रयास को विफल करने की योजना में सक्रिय हैं। जनवरी, १९८९ से लेकर अब तक के २० के लगभग दंगों में राजस्थान के विभिन्न भागों में २७ लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

विपक्ष से लोकसभा में केवल राजमाताएं पहुंचती रही हैं, तो कांग्रेस-इ से प्रभावी राजनेताओं की पत्नियों को ही लोकसभा से प्रतिनिधित्व मिला है।

दरअसल, राजस्थान में चुनावों की खबर ऐसे समय में आयी, जब रामशिला पूजन के 'हिमायती' और बाबरी मस्जिद के 'वफादार' दो-दो हाथ करने के लिए पूरे प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे थे। कोटा की तबाही के बाद यह आग सद्भाव के लिए मशहूर जयपुर शहर के शास्त्री नगर में भड़की और मारा गया शहर की चारदीवारी के बीच मुस्लिमबहुल क्षेत्र में बच्चों के लिए बर्फ के फूल बेचता रमेश सिंधी। प्रशासन और आम लोगों के नेक इरादों ने इसे जयपुर में नहीं बढ़ने दिया, लेकिन कोटा संभाग के झालावाड़ जिले के सरोला कस्बे में हिमायतियों और वफादारों को मारकाट से बचाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और एक जवान की मृत्यु हो गयी। शहर की यह बदमिजाजी कोटा संभाग के गांवों में आज भी कालिख पोत रही है। वहां भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर कस्बा और नांगौर जिले का लाडनू शहर मजहब के नाम पर कुछ और शव दफना अथवा जला रहा है। ऐसे में चुनावी मुद्दा अगर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तक सीमित रह गया, तो जहां विपक्षी एकता के लिए हुए गठबंधन बेमानी हो जायेंगे, वहीं सारे चुनावी नारे और वायदे भी अपना असर खो देंगे और विजय उसी की होगी, जिसे धर्माचार्य या मुल्ला मौलवी चाहेंगे।

—ओम सैनी

आम चुनाव

इस बार लड़ाई कांटे की होगी

१९८४ में मध्य प्रदेश की लोकसभा की सभी ४० सीटों पर कांग्रेस-इ ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार उसकी मुख्य टक्कर भाजपा से होगी जो बदली हुई परिस्थितियों में सशक्त हुई है और जिसने ३२ स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं। इस बार विपक्ष के मतों के बंटने की संभावना भी कम है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम रख पायेगी?

आगामी २२ और २४ नवंबर को लोकसभा चुनावों की आकस्मिक घोषणा ने चुनावी रणभेरी में हवा फूंकने का काम किया। तदुपरांत दिल्ली और भोपाल में टिकटों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो मारामारी हुई, उसने दो बातें उजागर कर दी: पहली यह कि सत्तारूढ़ कांग्रेस-इ में भितरघात का खतरा 'खतरे के निशान' के करीब है और दूसरा यह कि विपक्ष के नेताओं ने अतीत के छवि-हंता अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया है और उनमें दूरदृष्टि एवं व्यावहारिक सोच का अभाव है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस-इ ने इस दफा झमेलों और खतरों से बचने की युक्ति अपनायी। यही कारण है कि उसने नये चेहरों पर पुराने और परिचित चेहरों को तरजीह दी है। और-तो-और, कुछ ऐसे सांसदों को भी टिकटें थमायीं गयी हैं जो या तो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे अथवा जिन्हें टिकट देना पार्टी के हित में नहीं था। मप्र शासन में मंत्री रह चुके कर्नल अजयनारायण मुश्रान इस दफा जबलपुर से दुबारा चुनाव लड़ने के लिए नितांत अनिच्छुक थे और उन्होंने अपनी इच्छा से आलाकमान को अवगत करा दिया था। इसी प्रकार, बीड़ी व्यवसाय से संबद्ध दमोह से गत चुनाव में निर्वाचित डालचंद जैन भी दमोह से पुनः चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पुनरावृत्ति की लीक पर चलते हुए आलाकमान ने मुश्रान और डालचंद दोनों को पुराने निर्वाचन क्षेत्रों में उतार दिया है। इस बार माना जा रहा था कि सिवनी से अनेक कारणों से गार्गीशंकर मिश्र के बजाय किसी नये चेहरे को सामने लाया जायेगा। लेकिन भाग्य की बलिहारी और उससे बढ़कर जोखिम और बखेड़ों से बचने की आलाकमान की वृत्ति-अंततः टिकट गार्गी को मिला।

दुविधा की स्थिति: हालांकि, मोतीलाल वोरा से लेकर शिवभानु सोलंकी तक यह बार-बार दोहरा रहे थे कि उनकी चालीस सीटों पर पूरी तैयारी है, किंतु रायपुर, महासमुंद, जांजगीर, भोपाल, सतना, उज्जैन और टीकमगढ़ समेत ग्यारह सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में आलाकमान को पसीना आ गया। अर्जुन सिंह को लेकर लंबे समय तक दुविधा की स्थिति रही। उनका नाम सतना और भोपाल दोनों स्थानों से उछला। परिणामतः दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का चयन अंतिम दौर में हुआ। कांग्रेस की तैयारियों की पोल रायपुर और महासमुंद के प्रसंगों ने भी खोली। यह जगजाहिर था कि महासमुंद से वीसी शुक्ल चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद भी कांग्रेस-इ सम्यक रणनीति बनाकर वहां के लिए कोई दमदार प्रत्याशी समय रहते नहीं तलाश सकी। तिकड़मी राजनीति के तहत एक बारगी श्यामाचरण शुक्ल का नाम भी महासमुंद से सुझाया गया, लेकिन महासमुंद के बजाय रायपुर से चुनाव लड़ने को लालायित श्यामाचरण ने इस सुझाव का तरीके से प्रतिकार कर दिया। जिन सीटों पर नेतृत्व पसोपेश का शिकार रहा, उनमें रींवा जैसी महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। रींवा से मार्तण्ड सिंह को टिकट देना उनकी अस्वस्थता और उनके खिलाफ तीव्र असंतोष के कारण खतरे से खाली नहीं था, किंतु जीत के लिए राजघराने पर अवलंबित इंका ने उन्हें एक बार फिर टिकट दे दिया। यह बात दीगर है कि राजघराने के दो और सदस्यों—महारानी प्रवीण कुमारी और युवराज पुष्पराज सिंह ने भी २५ अक्तूबर को रींवा से नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी ओर, इस बीच मार्तण्ड सिंह का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि उन्हें नामांकन पत्र दाखिल किये बिना शासकीय विमान से बंबई जाना पड़ा। तो इंका ने उनकी पत्नी प्रवीण कुमारी को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया।

कांग्रेस को हराने के मंसूबे: विजयराजे सिंधिया

चारों ओर सुरक्षित सीटों से घिरी जांजगीर की हालत शुरू से एक अनार सौ बीमार की सी थी। यहां से भाजपा ने खरसिया में अर्जुन सिंह को कड़ी टक्कर देनेवाले दिलीप सिंह जूदेव को टिकट देने का संकेत पहले ही दे दिया था, मगर आलाकमान को यहां प्रत्याशी चुनने में अनावश्यक समय लगा। इसी प्रकार, समीपवर्ती रायगढ़ से कुमारी पुष्पा सिंह को दोहराकर कांग्रेस-इ ने अपनी विजय की संभावनाओं को अपने हाथों क्षीण किया है।

दिलचस्प चुनाव: भारतीय जनता पार्टी ने गुना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री राजमाता विजयराजे सिंधिया को चुनावी संग्राम में उतारकर गुना संसदीय चुनाव को रोचक और रोमांचक बना दिया है। गुना के अलावा जिन कुछ और सीटों के नतीजों पर लोगों की नजरें टिकी रहेंगी, वे हैं: मंदसौर, विदिशा, राजनांदगांव राजगढ़, जांजगीर, रायपुर, होशंगाबाद और झाबुआ। कांग्रेस-इ ने मंदसौर से बाल कवि वैरागी, होशंगाबाद से सेवादल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा, राजगढ़ से पूर्व प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है।

गुना: प्रारंभ से यह सिंधिया घराने के प्रभाव और वर्चस्व की सीट रही है। १९५७ में गुना ने सारे देश का ध्यान तब आकर्षित किया था, जब राजमहल का वैभव और उसकी देहरी छोड़कर राजमाता सिंधिया ने सक्रिय राजनीति के बीहड़ में पांव धरे थे और कांग्रेस-प्रत्याशी के तौर पर यहां से खड़ी हुई थीं। हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे से सीधी टक्कर में राजमाता करीब १.१८ लाख मतों से जीती थीं। इसके बाद १९६७

में राजमाता ने यहां से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वे स्वतंत्र दल की प्रत्याशी थीं। उन्होंने कांग्रेस के डीके जाधव को लगभग दो लाख मतों से मात दी। राजमाता की लोकप्रियता का आभास इससे हो सकता है कि उन्हें इस चुनाव में मिले २.३१ लाख मतों के विरुद्ध कांग्रेस को केवल ४५ हजार वोट मिले थे। १९७१ में इंग्लैंड से अध्ययन कर लौटे और राजनीति में नये-नये प्रविष्ट हुए युवा माधवराव सिंधिया ने पहला चुनाव ग्वालियर के बजाय गुना से लड़ा था। युवा माधव तब जनसघ के टिकट पर १.४० लाख वोटों से जीते थे। अगला चुनाव उन्होंने निर्दलीय और १९८० का चुनाव यहीं से कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर जीता। १९८४ में सिंधिया जब ग्वालियर से लड़े, तो यहां से उनके विश्वासपात्र सहयोगी महेंद्र सिंह को टिकट मिला था, जो इस बार पुनः कांग्रेस उम्मीदवार हैं।

कांग्रेस के कर्णधार: माधव राव सिंधिया

"मैंने मतदाताओं से किये ९९ फीसदी वायदे पूरे किये हैं," सांसद महेंद्र सिंह ने 'माया' से कहा। 'पेयजल समस्या' के निदान और इस क्षेत्र शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण को वे अपनी प्रमुख उपलब्धियां मानते हैं। गुना तथा शिवपुरी में हवाईपट्टी का निर्माण, गुना-शिवपुरी-ग्वालियर रेल लाइन का निर्माण तथा गुना से बदरवास तक मुसाफिर गाड़ी आदि उनके कार्यकाल की अन्य उपलब्धियां हैं। सौम्य और शालीन महेंद्र सिंह गुना में भाजपा के किसी और प्रत्याशी पर निश्चित ही भारी पड़ते, लेकिन भाजपा की ओर से राजमाता की उम्मीदवारी ने उनकी जीत पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। कारण यह कि राजमाता को इस अंचल में सर्वत्र सम्मान प्राप्त है और अतीत में वे दो बार गुना का लोस में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

खरगौन: इस सीट से पिछले दोनों चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर सहकारिता के महारथी सुभाष यादव विजयी रहे थे। पश्चिमी निमाड़ की इस सीट पर उनका सामना एक बार फिर रामेश्वर पाटीदार से होगा, जो १९७७ में चुनावी बाजी जीते थे। खरगौन जिले में, विशेषकर महेश्वर और कसरावद में पाटीदार समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में हैं। स्थानीय जन खरगौन में गत दिनों भड़की सांप्रदायिक हिंसा को सत्तारूढ़ दल के लिए घातक मानते हैं। इंका को दूसरा खतरा अंतर्कलह से है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता यादव समर्थकों और विरोधियों में बंटे हुए हैं। यादव विरोधियों की कमान अमोलकचंद छाजेड़, श्रीमती चंद्रकांता खोड़े, चांदमल लूनिया वीरेंद्र गौर और सीताराम साधो आदि नेताओं के हाथों में है। पार्टी के भीतर जबर्दस्त विरोध के बाद भी यादव का पलड़ा इसलिए मजबूत है, क्योंकि मंडियों, कमेटियों और सहकारी बैंकों में उनके कट्टर समर्थक आसीन हैं। साधनों की उन्हें कमी नहीं है। विधायकों में बड़वाह के राणा बलबहादुर, कसरावद के रमेशचंद्र मंडलोई, सेंधवा के भया सिह डाबर, राजपुर के बारकूभाई चौहान का सहयोग यादव को मिलेगा। इसके अलावा खरगौन में सहकारी बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, सूत मिल, अस्पताल, टीवी रिले केंद्र की स्थापना का लाभ उन्हें मिलेगा। किंतु खरगौन को रेलवे लाइन से न जोड़ पाने का आरोप अभी भी यादव के माथे है। कांग्रेस-इ को धुलकोट और राजपुर से हमेशा अच्छी लीड मिलती रही है, किंतु जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे इस बार सेंधवा, कसरावद और महेश्वर में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

कांग्रेस-इ ने इस दफा झमेलों और खतरों से बचने की युक्ति अपनायी। यही कारण है कि उसने नये चेहरों पर पुराने और परिचित चेहरों को तरजीह दी है। और-तो-और, कुछ ऐसे ऐसे सांसदों को भी टिकटें थमायी गयी हैं जो या तो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे अथवा जिन्हें टिकट देना पार्टी के हित में नहीं था।

राजगढ़: यहां पिछली बार निर्वाचित सांसद दिग्विजय सिंह इस बार फिर मैदान में हैं। वे पांडा-तराई प्रकरण में विवादास्पद रहे और फिर जनवरी में शक्ति-परीक्षण के कारण सुर्खियों में। प्रत्युत्पन्नमति और अपने ठहाकों के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह कल तक अर्जुन सिंह के दायें हाथ माने जाते थे, किंतु इधर वे अर्जुन सिंह से थोड़ा दूर हटे हैं। युवा विचार मंच और फिर किसान रथ के आयोजन में भाग न लेने के बाद उन्होंने ग्वालियर में क्षत्रिय महासभा के विजयादशमी के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। बताते हैं कि उन्होंने इस तरह के आयोजनों पर अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त की थी। बहरहाल, सितंबर में विजयपुर संयंत्र के उद्घाटन प्रसंग में राजीव गांधी जब गुना आये, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को काफी महत्व दिया। गुना के मतदाता मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कई वायदों को पूरा किया है। सिरोंज में रापनि डिपो, पालीटेक्नीक संस्थान की शुरुआत, विजयपुर कारखाने की स्थापना, पचौर में नवोदय विद्यालय, आरौन को तहसील का दर्जा और वहां न्यायालय व कोषालय का प्रारंभ तथा राघौगढ़ में संजयसागर का श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है। इसके बाद भी अगर यहां भाजपा-जद का संयुक्त प्रत्याशी खड़ा होता है, तो उनका रास्ता आसान नहीं होगा। राजगढ़ जिला इंका के अध्यक्ष

मुकाबले की टक्कर: कमलनाथ

भाजपा ने गुना से राजमाता विजयराजे सिंधिया को चुनावी संग्राम में उतारकर चुनाव को रोचक और रोमांचक बना दिया है।

मांगीलाल भंडारी, राघोगढ़, ब्यावरा, सिरोंज, राजगढ़, चाचौडा, सारंगपुर व खिलचीपुर से मिलकर बने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अतीत में डा० शंकरदयाल शर्मा, डा० वसंतकुमार पंडित और जगन्नाथराव जोशी आदि कर चुके हैं। यहां विपक्ष का जनाधार भी विद्यमान है। यहां मतदाताओं की संख्या नौ लाख छह सौ छियान्नबे है जो १११० मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आदिवासी-बहुल झाबुआ से दिलीप सिह भूरिया की उम्मीदवारी पहले से तय मानी जा रही थी। १९७७ में जनता पार्टी के भगीरथ भंवर से हारने के बाद भूरिया ने १९८० और फिर १९८४ में यहां से चुनाब जीता था। भूरिया की परेशानी यह है कि यहां संगठन निष्क्रिय है और अधिकांश विधायक उनके खिलाफ हैं। इंका पर्यवेक्षक द्वय रणजीत सिह जूदेव और सत्या बहन जब यहां आये थे, तो चार इंका विधायकों एवं पांचों जनपद अध्यक्षों ने उनके नाम का विरोध किया था। केवल अलीराजपुर के मगन सिह पटेल ने ही उनकी पैरवी की थी। भूरिया विरोधी गुट ने थांदला से विधायक कांतिलाल भूरिया के नाम पर दांव लगाया था, लेकिन टिकट अंतत: दिलीप सिंह को मिला। इस संसदीय क्षेत्र में अलीराजपुर, जोबट, झाबुआ, थांदला, पेटलावद, सैलाना और रतलाम शहर व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों का समावेश है। पिछले चुनाव में १.३४ लाख मतों से विजयी भूरिया को आठों विधानसभाई क्षेत्रों में लीड मिली थी, लेकिन कुछ माह बाद हुए विधानसभाई चुनावों में कांग्रेस-इ के मतों में करीब ४८ हजार वोटों की कमी आ गयी थी और रतलाम शहर की सीट भाजपा के खाते में चली गयी थी।

मंदसौर : अफीम की खेती के लिए विख्यात मंदसौर १९६२ से लेकर १९८० तक विपक्ष के खाते में दर्ज रहा। १९६२ से १९७७ तक यहा से जनसंघ के प्रत्याशी जीतते रहे और १९७७ मे लोकदल प्रत्याशी विजयी हुआ। जनसंघ के डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय ने १९७१ और १९७७ में क्रमश: बालकवि बैरागी और बंशीलाल गांधी को परास्त किया था। १९८० में कांग्रेस के (स्व) भंवरमल नाहटा ने पहली बार डा० पांडेय को करीव तीन हजार वोटों से हराकर यहां कांग्रेस का परचम लहराया था। १९८४ की सहानुभूति लहर में कांग्रेस-इ के बालकवि बैरागी लगभग ६० हजार वोटों से विजयी रहे। इस बार फिर मुकाबला दोनों पुराने मल्लों के बीच है।

जावरा, मनसा, गरेठि, सुआसरा, सीतामऊ, मंदसौर, नीमच और जावद विधानसभा क्षेत्रों से निर्मित मंदसौर की विशेषता यह है कि यहां राजनीतिक चेतना का निरंतर प्रसार हो रहा है। इसकी पुष्टि विगत चुनावों में मतदान के प्रतिशत से होती है। १९५७ में ४३.१० प्रतिशत के मुकाबले १९६२ और १९६७ में क्रमश: ५७.२८ और ६१.१७ प्रतिशत वोटरों ने वोट डाले। १९७७ की जनता लहर में ६८.५० प्रतिशत वोट पड़े। १९८० में लगभग इतने ही मतदान के उपरांत १९८४ मे ग्राफ फिर ऊपर उठा और ७१.६८ प्रतिशत मतदान हुआ। अब चूंकि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ही लहर का अभाव है, अत: यह देखना रोचक होगा कि विपक्ष के इस पुराने गढ़ में आठ लाख से अधिक मतदाता अपने दोनों सुपरिचित प्रत्याशियों में से किसका विजय तिलक करते हैं? फिलहाल, ऊंट की करवट का अनुमान मुश्किल है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बालकवि बैरागी को यहां असंतोष और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्हें इसका उत्तर देना होगा कि उन्होंने दिल्ली जाने के बाद मंदसौर से कितना सरोकार रखा, क्षेत्रीय विकास के लिए क्या किया और कितने वायदे पूरे किये?

—एसपी त्रिपाठी

भाजपा की चुनौती

"मप्र को भाजपा का गढ़ कहना गलत है", भूतपूर्व प्रदेश इंकाध्यक्ष व राजगढ़ से सांसद दिग्विजय सिंह कहते हैं, "कुल करीब दस प्रतिशत वोट भाजपा की जमा पूंजी है। भाजपा ऋणात्मक मतों पर आस लगाये बैठी है।" इसी क्रम में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया ने 'माया' से कहा, "मप्र में भाजपा की कोई चुनौती नहीं है। भाजपा अपनी संकीर्ण विचारधारा से आज तक ऊपर नहीं उठ सकी है। अपनी संकीर्ण विचारधारा और रीति-नीति के चलते व्यापक दृष्टिकोण के भारतीय समाज में भाजपा कभी भी चुनौती नहीं हो सकती।"

कांग्रेस-इ के अधिकांश नेता इसी लहजे में बात करते हैं, किंतु पटवा, सारंग और जोशी से लेकर ठाकरे तक का कहना है कि अधिकांश सीटों पर इस चुनाव में भाजपा जीतेगी। वे कहते हैं कि इस बार चुनाव बगैर किसी लहर के हो रहे हैं। हमारे पास धन और साधन भले ही कम हों, किंतु समर्पित और संकल्पित कार्यकर्ताओं की फौज है। प्रांतीय कोषाध्यक्ष कैलाश सारंग कहते हैं, "हम जनता से वोट भी मांगेंगे और नोट भी।"

इस समय भाजपा की प्रांतीय इकाई में १६ पदाधिकारियों एवं ५१ नियमित सदस्यों सहित कुल १४७ लोग हैं। पार्टी के चुनाव प्रचार का दायित्व दस मोर्चों और दो प्रकोष्ठों के कंधों पर रहेगा। १८ से २० वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को लुभाने और रिझाने में इस दफा भाजयुमो (युवा शाखा) की खासी भूमिका रहेगी। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजयुमो का काम करीब २७ लाख युवा मतदाताओं को आकर्षित करना होगा। इसी क्रम में भेरूलाल पाटीदार की अगुवाई में भाजपा का किसान मोर्चा, श्रीमती कुसुम मेंहदेले के नेतृत्व में महिला मोर्चा, बाबूलाल जैन और जगतनारायण जोशी के साझा नेतृत्व में व्यापारी मोर्चा, तनवीर अहमद के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा चुनाव अभियान में उतरने को सन्नद्ध हैं। भाजपा के हरिजन मोर्चे और झुग्गीवासी महासंघ की कमान नारायण सिंह केसरी और मांझी मोर्चे की बागडोर मोती कश्यप के हाथों में है। भाजपा के पंचायत और सहकारिता प्रकोष्ठ भी अर्से से सक्रिय हैं और वे भी चुनाव-प्रचार में हाथ बंटायेंगे।

कुछ लोगों के लिए यह जानकारी बहुत दिलचस्प हो सकती है कि उसने सभी नौ संभागों में पूर्णकालिक संगठक नियुक्त किये हैं। जबलपुर में मनोहर राव, रायपुर में गोविंद सारंग, बिलासपुर में केशव दवे, ग्वालियर में डा० जनार्दन, उज्जैन में कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर में कमलचद राठौर और सागर में ईवर माधवानी पूर्णकालिक संगठक हैं। मजे की बात यह है कि ये सभी अविवाहित हैं। पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित ये संगठक चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा से बरी हैं। अविवाहित होना संगठक पद की अर्हता-सी है। कुछ समय पहले सुरेश देशपांडे रींवा के संगठक थे, किंतु विवाह करने पर उन्हें इस पद से से हटा दिया गया। इन दिनों एनपी गुप्ता अस्थाई तौर पर रींवा और विधायक बाबूलाल गौर भोपाल संभाग का काम देख रहे हैं। भाजपा ने शेजवलकर को ग्वालियर, कुमारी उमा भारती को सागर, बाबूराव परांजपे को जबलपुर, रमेश बैश को रायपुर, सुखेंद्र सिंह को रींवा, विक्रम वर्मा को इंदौर और दिलीपसिंह जूदेव को बिलासपुर संभाग का प्रभारी बनाया है। केंद्रीय नेताओं में राजमाता सिंधिया, अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभायेंगे। फिलहाल प्रचार के लिए कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश सारंग और सुंदरलाल पटवा को दौरों के लिए एक-एक एम्बेसेडर कार, प्यारेलाल खंडेलवाल को मारुति और एनपी गुप्ता को एक जीप दी गयी है।

—एसपी त्रिपाठी

चुनाव '८९

सीधी मुठभेड़ की संभावना

दिल्ली की सात संसदीय सीटों में से १९६७ में जनसंघ ने छह और १९७७ में जनता पार्टी ने सातों सीटें कांग्रेस से छीन ली थीं—क्या १९८९ में भी दिल्लीवासी वह इतिहास दोहरायेंगे ?

अब दिल्ली दूर नहीं है। चुनाव घोषित होने के साथ ही दिल्ली फतह करने की जद्दोजहद शुरू हो गयी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दिल्ली को अपना गढ़ मानते हैं और यह बात लगभग तय है कि सात में से पांच सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा और दिलचस्प मुकाबला होगा। दिल्ली में लोकसभा की सात सीटें हैं—नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, बाहरी दिल्ली, पूर्व दिल्ली, चांदनी चौक, सदर और करौल बाग (आरक्षित)। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें कांग्रेस ने हथियाई थीं। १९७७ के आम चुनाव को छोड़कर भाजपा को दिल्ली में कभी सातों सीटें नहीं मिलीं। १९६७ में भाजपा को ६ सीटें मिली थीं, लेकिन बाहरी दिल्ली पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश के जरिए कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। १९८० के चुनाव में भाजपा के एक मात्र सफल उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी थे जो नयी दिल्ली की सीट कांग्रेस से छीन सके थे। शेष सभी दिग्गज भाजपा नेता धूल चाटते नजर आये थे और १९८४ के चुनाव में तो भाजपा का पूरी तरह पत्ता साफ हो गया था। उसके सभी दिग्गज नेता विजय कुमार मल्होत्रा, सिकंदर बख्त, कंवरलाल गुप्त, सुरेंद्र पाल रथवाला और मदनलाल खुराना परास्त हो गये थे। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों में तो कांग्रेसी सांसदों का झंडा फहराया, पर महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम में भाजपा की तूती बोलती रही है। वास्तव में ये दो स्थानीय इकाइयां ही दिल्ली का कामकाज तथा विकास योजनाएं देखती हैं और इनमें भाजपा ने अपने शासन काल के दौरान दिल्ली में काफी काम करने का दावा किया है। इसी शानदार रिकार्ड के दम पर भाजपा दिल्ली को अपना गढ़ मानती है और कांग्रेस का सफाया करने का दावा करती है। फिलहाल परिषद और निगम दोनों पर ही १९८३ से कांग्रेस का कब्जा है और इसके चुनाव दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित सरकारिया कमेटी के बहाने टाले जा रहे हैं। न तो कमेटी की रिपोर्ट ही निर्धारित समय (मई-जून १९८९) पर पेश की जा सकी और न ही चुनाव कराये गये। इसको लेकर भाजपा आंदोलन करती रही है। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने का वायदा पूरा न करने को भाजपा कांग्रेस के विरुद्ध अपना प्रमुख हथियार बनायेगी।

अपूर्ण वायदे: इसके अलावा १९८३ के नगर निगम तथा परिषद के चुनावों में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष हर किशन लाल भगत द्वारा जारी घोषणा पत्र में दिल्ली को विधानसभा देने, अवैध कालोनियों को नियमित करने, मलिन बस्तियों का सुधार करने, लीज प्रथा समाप्त करने तथा फुटपाथी व्यापारियों को खोखा देने जैसे ३४ वायदे किये गये थे। भाजपा इन वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को जनता की अदालत में खड़ा करेगी। इसके जवाब में कांग्रेस अपनी तमाम योजनाओं—जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण के अलावा पंचायत और नगर पालिका विधेयक की विपक्ष द्वारा मुखालफत के मुद्दे को लेकर जनता तक पहुंचेगी और विपक्ष को जन-विरोधी ठहराकर जनमत अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास करेगी। भगत ने तो चुनाव घोषित होने के एक सप्ताह बाद अपने संसदीय क्षेत्र में रैली निकालकर विपक्ष पर अपना पहला प्रहार किया था। इसके अलावा २० अक्तूबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली के पट्टे पर दिये गये सभी आवासीय भूखंडों और फ्लैटों को पट्टे से मुक्त कर फ्री-होल्ड करने का निर्णय करके मतदाताओं को लुभाने का अपना पहला पत्ता खेला है।

वर्चस्व खतरे में: एचकेएल भगत

प्रतिष्ठा की लड़ाई: लालकृष्ण आडवाणी

पूर्वी दिल्ली, सात संसदीय क्षेत्रों में बाहरी दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा क्षेत्र है, जहां १४ लाख ७८ हजार मतदाता हैं। १९८४ में इनकी संख्या ८,३२,३२४ थी। इनमें ८४,६३५ मतदाता १८ से २१ वर्ष की आयु के हैं जो पहली बार मत देंगे। भगत ने पिछले चुनाव में ७६.९५ प्रतिशत मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी किशोरलाल (जनता) को बुरी तरह परास्त किया था। १९८० के चुनाव में भी किशोरलाल को भगत से २१ प्रतिशत कम मत मिले थे। १९७७ की लहर में किशोर जीत गये थे।

केन्द्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर भगत के बाद दूसरे ऐसे इंका नेता हैं, जिनका दिल्ली में अच्छा प्रभाव है। अपनी-अपनी हैसियत को लेकर भगत-टाइटलर के बीच चलनेवाला शीत युद्ध यहां हमेशा चर्चा में रहता है। सदर निर्वाचन क्षेत्र में पांच लाख चार हजार ४५३ मतदाता हैं, जिनमें लगभग २७ हजार नये युवा मतदाता शामिल हुए हैं। टाइटलर यहां से पिछले दो बार से सांसद हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल खुराना को हराया था। १९७७ में यहां से कंवरलाल गुप्त (जनता) जीते थे। उनका निधन हो जाने से विपक्ष के पास टक्कर का उम्मीदवार नहीं रहा। यह सीट भाजपा के कोटे में

है और उसने विजयकुमार मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मल्होत्रा १९७७ में दक्षिण दिल्ली से 'कैम्पा कोला' वाले चरण जीत सिंह (कांग्रेस) को हराकर संसद में पहुंचे थे। १९८० में वे इस सीट पर चरणजीत सिंह से और १९८४ में ललित माकन से हार गये थे। मल्होत्रा दिल्ली महानगर परिषद के मुख्यकार्यकारी पार्षद भी रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि दिल्ली में भाजपा ने जितना काम करके दिखाया है, उसको देखते हुए उनका चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है। टाइटलर की उम्मीदवारी को लेकर भी काफी अटकलबाजियां चल रही थीं कि इस बार कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देगी। टाइटलर ने टिकट पाने की जोड़तोड़ तेज कर दी थी—संसदीय क्षेत्र से रोज सैकड़ों टेलीग्राम प्रधानमंत्री के पास पहुंचने लगे थे कि टाइटलर को ही सदर से टिकट दिया जाये। टाइटलर और मल्होत्रा के बीच बड़ा रोचक मुकाबला होगा और हार-जीत बहुत कम मतों के अन्तर से होगी।

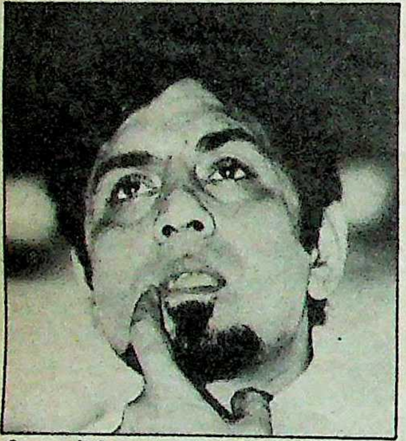

टिकट पाने में कामयाब : जगदीश टाइटलर

टाइटलर ने टिकट पाने की जोड़तोड़ तेज कर दी थी—संसदीय क्षेत्र से रोज सैकड़ों टेलीग्राम प्रधानमंत्री के पास पहुंचने लगे थे कि टाइटलर को ही सदर से टिकट दिया जाये। टाइटलर और मल्होत्रा के बीच बड़ा रोचक मुकाबला होगा और हार-जीत कम मतों के अंतर से होगी।

बड़ी सीट : बाहरी दिल्ली सबसे बड़ी सीट है। इसमें १५ लाख ७० हजार के करीब मतदाता हैं, जिनमें ९७००० नये युवा मतदाता हैं। यहां से कांग्रेस ने चौधरी भरत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जो १९८० में ७२.८ प्रतिशत मत पाकर लोकदल के तारीफ सिंह से जीते थे। १९८० में यहां से कांग्रेस के सज्जन कुमार (प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा महामंत्री), १९७१ में चौधरी दिलीप सिंह (कांग्रेस) १९६७ में कांग्रेस के ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश जीते थे। १९७७ में चौधरी ब्रह्मप्रकाश ही लोकदल के टिकट पर जीते थे। कांग्रेस द्वारा भरत सिंह को टिकट दिये जाने से सज्जन कुमार के विरोधियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया था। इस क्षेत्र में सज्जन कुमार का अच्छा प्रभाव है। भरत भी सज्जन कुमार को टिकट दिये जाने के लिये जोर लगा रहे थे। सज्जन कुमार के खेमे की दलील है कि हरियाणा की सीमा से लगे होने के कारण देवीलाल और उनके सांसद पुत्र ओम प्रकाश चौटाला अपने प्रभाव का विपक्षी उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस कारण तगड़ा उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। जिसके लिए सज्जन कुमार पूरी तरह सक्षम हैं। पर आलाकमान ने भरत सिंह को ही .उम्मीदवार बनाने का फैसला कर भगत गुट को धक्का पहुंचाया। इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में मतदाताओं की संख्या लगभग तीन लाख है, जिनमें जाट, गूजर, यादव आदि अधिक हैं। लगभग ८ लाख मतदाता झुग्गी-झोपडियों और अनधिकृत बस्तियो में रहते हैं।

व्यापारिक गढ़ : चांदनी चौक की व्यापारिक गढ़ वाली सीट से कांग्रेस ने सांसद जयप्रकाश अग्रवाल को ही दुबारा टिकट दिया है। चांदनी चौक दिल्ली की सबसे छोटी सीट है, जहां केवल तीन लाख ८१ हजार ४१४ मतदाता हैं। यहां व्यापारी काफी तादाद में हैं और इनमें वैश्य काफी हैं। भाजपा की जीत का आधार यही वोट बैंक है। यहां मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। रामजन्मभूमि का मुद्दा यहां काफी निर्णायक रहेगा—हिंदू और मुस्लिम मतों के सीधे दो पाटों में बंट जाने की आशंका है।

दिल्ली के एकमात्र आरक्षित क्षेत्र करौल बाग से पिछले चुनाव में श्रीमती सुंदरवती नवल प्रभाकर (कांग्रेस) निर्वाचित हुई थीं। करोल बाग छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां ४ लाख ८० हजार ७२३ मतदाता हैं, जिनमें २५,९१३ युवा हैं। दो प्रतिष्ठावाली सीटों—नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जनता की आंखें टिकी हैं, जहां से कांग्रेस की श्रीमती मोहिनी गिरि के मुकाबले भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी खड़े हैं। नई दिल्ली से रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत सांसद हैं। वे पिछली बार पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे और कंवरलाल गुप्त को हराया था। राजनीतिक हल्कों में काफी अरसे से यह चर्चा चल रही थी कि पंत, यहां अपनी स्थिति कमजोर पाने के कारण अपनी पैतृक सीट नैनीताल वापस जाना चाहते थे। पर कांग्रेस की ताजा सूची में नैनीताल से उप्र के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के 'खास आदमी' सत्येन्द्र नारायण गुड़िया का नाम नजर आने पर पंत इतने नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा प्रेस सम्मेलन बुलाकर कहीं से भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, तब अंतिम क्षणों में नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस-इ ने पूर्व राष्ट्रपति वीवा गिरि की पुत्री मोहिनी गिरि को अपना प्रत्याशी बनाया।

राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के निवास, वीआईपी तथा साफ-सुथरी सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों और महत्वपूर्ण कार्यालयों को समेटे यह क्षेत्र पार्टी और मुद्दों के बजाय उम्मीदवार के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित होता है। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी, सीएम स्टीफेन और पंत जैसे बाहरी व्यक्ति भी यहां से जीतकर संसद में पहुंचे। यहां कुल ४,२७,८८६ मतदाता हैं। जिनमें २१,८५५ युवा मतदाता हैं।

कड़ा मुकाबला : विजय कुमार मल्होत्रा

इस सीट पर मुकाबला बहुत रोचक होगा और कांग्रेस—भाजपा के उम्मीदवारों में जिसका व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावशाली होगा, वही विजयी होगा।

दक्षिणी दिल्ली का मुकाबला कम भी दिलचस्प नही होगा। १९८४ में यहां से डंका के ललित माकन निर्वाचित हुए थे जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आतंकवादियों ने मार डाला। उनके बाद मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यहां से विजयी हुए। दिल्ली के इस तीसरे बड़े निर्वाचनक्षेत्र में ८ लाख ५४ हजार २३३ मतदाता हैं, जिनमें ४४१०० युवा मतदाता हैं।

—बिशन कुमार

मजोर पाने
ापस जाना
ों नैनीताल
री के 'खास
का नाम
कि उन्होंने
भी चुनाव
म क्षणों में
-इ ने पूर्व
ा गिरि को

निवास,
कर्मचारियों
ालियों को
के वजाय
ावित होता
वाजपेयी,
व्यक्ति भी
यहां कुल

८५५ युवा

चक होगा
में जिसका
ही विजयी

कम भी
से डंका के
हैं श्रीमती
वादियों ने
मुख्यमंत्री
नी के इस
८४ हजार
मतदाता

न-कुमार

स्टील से अधिक लम्बी आयु किसी की नहीं

STAR TRAK
STEEL BELTED RADIAL
JK TYRE

जे के स्टार ट्रैक

एकमात्र स्टील बैल्टेड कार रेडियल

विश्व में 95% वाहन इस्पात की मज़बूती के लाभ उठा रहे हैं तो क्या आश्चर्य।

जे के टायर का स्टार ट्रैक ये सभी लाभ आपके लिए ले आया है।

- ▲ 70% तक अधिक माइलेज
- ▲ 7% तक ईंधन की बचत
- ▲ सड़क की बेजोड़ पकड़
- ▲ वाहन चालन में अभूतपूर्व आराम।

कारों तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों के प्रमुख निर्माता अपने वाहनों के लिए सब से पहले जे के रेडियल्स को चुनते हैं।

जेकेटायर

आई.डी.बी.आई.के
पूँजी-बांड
पूँजी लाभ कर से
छूट पाने का आकर्षक साधन

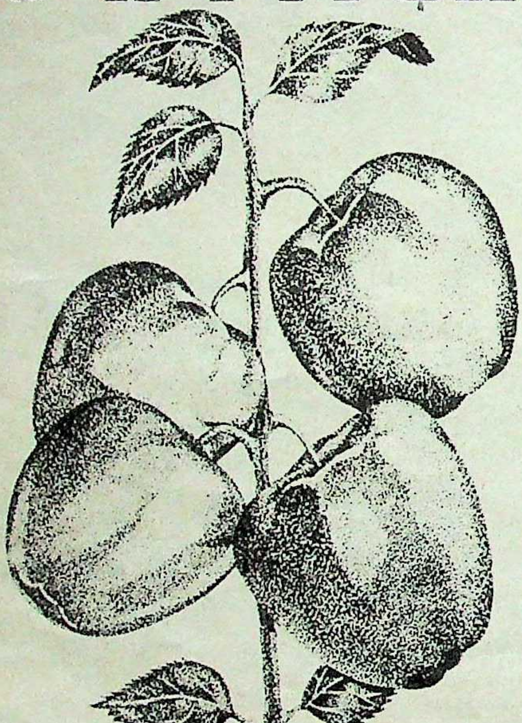

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टावर, कफ़ परेड, कोलाबा, बम्बई 400005.

Subhagya-B/89 HN

लोकसभा चुनाव

प० बंगाल का निर्णय नये मतदाताओं के हाथ में

पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का गढ़ कहा जाता है। किंतु सन १९८४ में कांग्रेस ने वहां की कुल ४२ लोकसभा सीटों मे से १६ स्थानों पर कब्जा कर लिया था। आसन्न आम चुनाव में कांग्रेस इस राज्य मे कुछ करिश्मा दिखा पायेगी अथवा परिणाम फिर से वामपंथी मोरचे के पक्ष में जायेगा, यह इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही एक घोषणा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि इस बार कांग्रेस को राज्य में दो से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी जबकि अजित पांजा का दावा है कि कांग्रेस की विजय २५ सीटों पर सुनिश्चित है। दोनों वक्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण माने जा रहे हैं।

इस चुनाव में कांग्रेस ने सभी ४२ स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये हैं। जनता दल से चुनाव समझौते के फलस्वरूप मोरचे ने उत्तर-पश्चिम कलकत्ता की सीट जनता दल के अशोक सेन के लिए छोड़ दी है। शेष स्थानों का मोरचे में शरीक दलों के बीच विभाजन इस प्रकार है: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी-३१, आरएसपी-४, भाकपा-३ तथा फारवर्ड ब्लाक-३। ऐसे में क्या कांग्रेस राज्य में अपने १६ स्थान सुरक्षित रख पायेगी? इस परिप्रेक्ष्य में राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव पर विहंगम दृष्टि डाल लेना उचित होगा।

पश्चिम बंगाल का पिछला विधानसभा चुनाव १९८७ में हुआ था। इस चुनाव में वामपंथी मोरचे को २९४ सीटों में से २५१ सीटें प्राप्त हुई थी (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अकेले १८७ स्थानों पर विजय मिली थी)। कांग्रेस ने भी सभी २९४ स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, किंतु उसे मात्र ४० सीटें मिलीं। पिछले तीन चुनावों में मोरचे को प्राप्त वोटों का औसत ४२.८५ प्रतिशत रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को ४१.८२ प्रतिशत वोट मिले और वाम मोरचे को ५२.९४ प्रतिशत, जिसमें ३९.१९ प्रतिशत वोट माकपा के पक्ष में गये। इस आंकड़े से लगता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी की टक्कर है, किंतु इस चुनाव में अंत तक किसका पलड़ा भारी होगा, यह बहुत कुछ निर्भर करता है, १८ से २० वर्ष के नये वोटरों पर जिनकी संख्या राज्य में २५, १५, ६०४ है।

लीग की नयी चाल: पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने ३६ सीटों पर लड़कर मात्र एक स्थान प्राप्त किया था तथा ७० सीटों पर माकपा का समर्थन किया था। इस चुनाव में लीग की भूमिका क्या रहेगी, यह बात भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी ही। राज्य के मुस्लिम लीग के सदर हसनुज्जमा का राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल बरकत गनी खां चौधरी के दिल्ली निवास पर देखा जाना लीग द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिये जाने की संभावना की ओर इशारा माना जा रहा है। राज्य की लगभग २१.५ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम संप्रदाय की है। शाहबानो मामले और राम जन्भूमि-बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसका प्रभाव प० बंगाल पर भी पड़ना स्वाभाविक है। यद्यपि वहां स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, फिर भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंगाल में रामशिला-पूजन का आयोजन इस बात का द्योतक है कि प्रतिक्रियावादी हवा की चपेट से इस समय बंगाल भी मुक्त नहीं है। ज्योति बसु का दावा है कि बंगाल की जनता ने सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडप में शिलापूजा का कथित प्रयास विफल कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी यह हिदायत दे रखी है कि शिलापूजा या यज्ञादि खुली जगहों पर न करने दिया जाये। जुलूस निकालने तथा माइक आदि के द्वारा औरों को भड़काने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि शिलापूजन से संबंधित जुलूस तथा अयोध्या में राममंदिर के शिलान्यास के प्रस्तावित अनुष्ठान पर रोक लगायी जाये। वामपंथी मोरचे द्वारा भाजपा के संपूर्ण विरोध तथा लोकदल व जनता दल द्वारा भाजपा के साथ चुनाव गठबंधन किये जाने की स्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रीय मोरचे में शामिल न होने की स्पष्ट नीति से मुस्लिम वोटरों का झुकाव उनकी ओर हो भी सकता है।

२५ सीटों के सपने: अजित पांजा

सीधा मुकाबला: इस तरह राज्य की ४२ सीटों पर वामपंथी मोरचे और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की ही उम्मीद है। भाजपा की इस घोषित नीति का कि वह सर्वत्र कम्युनिस्टों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, प० बंगाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां भाजपा का कोई जोर नहीं है। फिर भी इन सीटों पर खड़े अन्य उम्मीदवार कितने वोट काटने में समर्थ होते हैं, इसका भी प्रभाव चुनाव के नतीजे पर अवश्य पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तथा वामपंथी मोरचे के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों ने कुल १३,७०,९१४ वोट हथिया लिये थे, यद्यपि उन्हें कुल ३ सीटें ही मिलीं। ये वोट कुल वैध वोटों के ५.२ प्रतिशत थे। इसके अलावा इस बार १८ से २० वर्ष के नये वोटरों की संख्या कुल वोटरों की पिछली संख्या से लगभग दस प्रतिशत अधिक होगी। यूं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस युवा वोट का विभाजन दोनों शिविरों में लगभग बराबर-बराबर होगा। किंतु इस विषय में सही अटकल लगाना टेढ़ी खीर है और हो सकता है कि ये दस प्रतिशत अतिरिक्त वोटर ही संसदीय

युवा वोट इधर: प्रियरंजन मुंशी

Sobhagya-8/89 HN

चुनाव के परिणामों के निर्णायक हों।

बेदम मुद्दे : माकपा की राज्य समिति के सचिव तथा राज्य वामपंथी मोरचे के अध्यक्ष सरोज मुखर्जी ने हाल ही एक वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अभियान में उनकी पार्टी राजीव गांधी के व्यक्तिगत आचरण पर आक्रमण नहीं करेगी। २३ अक्तूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस में विमान बसु के यह कहने पर कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 'गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है' का नारा दिया जा रहा है और यह नारा जनप्रिय भी है, सरोज मुखर्जी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है तथा प० बंगाल में इस तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी। फिर भी राजीव सरकार की दुर्नीति तथा केंद्र द्वारा राज्य को उचित धन न दिये जाने का प्रसंग वामपंथी मोरचे का इस चुनाव अभियान में मुख्य हथियार होगा। उदाहरण के लिए वक्रेश्वर ताप-विद्युत केंद्र के लिए अनुमोदन न मिलना, कलकत्ता पौर-सभा द्वारा मांगे गये १००० करोड़ रुपए का भुगतान न होना, उत्तरी बंगाल में एक भी भारी उद्योग स्थापित न हो पाना आदि चुनाव के मुद्दे बन गये हैं।

कांग्रेस के पास भी माकपा विरोधी हथियार हैं। मुख्यमंत्री ज्योति बसु के विरुद्ध बंगाल लैंप, ट्राम, गैस-टर्बाइन, पार्क की जमीन बेचने आदि से संबंधित भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, जिन्हें कांग्रेस ने पिछले दिनों भरपूर उछाला है।

> कलकत्ता, हावड़ा, हुगली तथा चौबीस परगना के अधिकांश स्कूल-कालेजों की छात्र यूनियनों का इस साल कांग्रेस संचालित छात्र परिषद के दखल में चले जाना भी इस बात का संकेत है कि शहरी अंचल में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। कुछ स्थानों पर वामपंथियों को कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी में परिणाम गोरखा हिल काउंसिल के समर्थन पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा १५ अक्तूबर को २८०० करोड़ रुपए की लागत से बननेवाली हलदिया पेट्रोकेमिकल्स परियोजना जो पिछले १२ वर्षों से खटाई में थी, की राजीव गांधी ने आधारशिला रखी। यह कदम कांग्रेस के चुनाव अभियान के पक्ष में है, जिसे वामपंथी मोरचा चुनाव-स्टंट की संज्ञा दे रहा है।

पश्चिम बंगाल के शहरी अंचल तथा औद्योगिक क्षेत्र में कांग्रेस का जोर अधिक है। १९८४ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में रही। कलकत्ता, हावड़ा, हुगली तथा चौबीस परगना के अधिकांश स्कूल-कालेजों की छात्र यूनियनों का इस साल कांग्रेस संचालित छात्र परिषद के दखल में चले जाना भी इस बात का संकेत है कि शहरी अंचल में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। कुछ स्थानों पर वामपंथियों को कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी में परिणाम गोरखा हिल काउंसिल के समर्थन पर निर्भर करेगा। झाड़ग्राम, पुरुलिया आदि निर्वाचन क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोरचा तथा जयनगर और मथुरापुर में एसयूसीआई माकपा के विरोध में जा सकते हैं। ये पार्टियां अब वामपंथी गठबंधन में नहीं हैं। वे यदि प्रत्येक सीट पर पचास हजार के आसपास भी वोट काट सकें तो माकपा के लिए मुश्किल हो जायेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गुट के कुछ विक्षुब्ध नेताओं के नक्सलपंथियों से जा मिलने से कृष्णनगर, नवद्वीप तथा बोलपुर में वामपंथी मोरचे के लिए कठिनाई होगी।

औद्योगिक क्षेत्र में वामपंथियों तथा कांग्रेसियों के पलड़े बराबर हैं तथा कुछ सीटों के दोनों ही पक्षों के हाथ से निकलने के आसार हैं। कुलमिलाकर पश्चिम बंगाल में ४२ सीटों में से अधिकांश में कांटे का मुकाबला है तथा परिणाम में निर्णायक भूमिका नये वोटर निभायेंगे।

—रमाप्रसाद घोषाल

मुफ्त
रीटा प्रत्येक सिलाई मशीन के साथ एक टाइमपीस
जल्दी कीजिए! योजना सीमित अवधि के लिए है।
IS:1610
ISI
Rita Mechanical Works
रीटा
—आजीवन सेवा के लिए
रीटा मैकेनिकल वर्क्स लुधियाना

स की विजय
त्ता, हावड़ा,
कांश स्कूल-
साल कांग्रेस
ले जाना भी
ल में कांग्रेस
मपंथियों को
र्जलिंग तथा
ल काउंसिल
म, पुरुलिया
क्ति मोरचा
एसयूसीआई
पार्टियां अब
प्रत्येक सीट
ट काट सके,
ी जायेगी।
ुब्ध नेताओं
कृष्णनगर,
रचे के लिए

थियों तथा
ुछ सीटों के
आसार हैं।
सीटों में से
परिणाम में
गे।
ाद घोषाल

शुरू से ही हर पल का साथ !

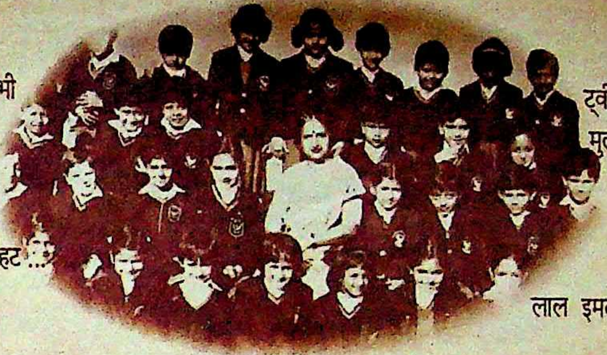

कितने ही मौसम आये और चले गये। साल भी
जाने कितने बदल गये ...लेकिन
लाल इमली धारीवाल के क्या कहने !
सदाबहार ... मनमोहक ... शानदार ...
गर्मियों में दिल गुदगुदायें, सर्दियों में गर्माहट ...
हर मौके के लिए बेमिसाल सूटिंग,

ट्वीड्स, ब्लेज़र मैटीरियल, कम्बल, नर्म ...
मुलायम ... गर्म ... और बुनाई का ऊन ...
यही तो है लाल इमली धारीवाल !
पूरी एक शताब्दी से
उत्तमता की परंपरा के प्रतीक
लाल इमली धारीवाल को आज ही से अपनाइये !

पहली पसंद के क्या कहने !

Lal-imli
Dhariwal

उत्तमता की
११२ साल
परंपरा के

adEnvoys

"पिछले दशक में ही सिर्फ लोहा निर्माण के क्षेत्र में हमने ऊर्जा के रूप में १०० करोड़ रु. की बचत की है।"

यदि श्री एल. एम. चटर्जी, ब्लास्ट फर्नेस के डिविजनल मैनेजर को अपनी कम्पनी की उपलब्धि पर गर्व है तो शायद यह स्वाभाविक ही है।

ज्यों ज्यों दुनिया का ऊर्जा भण्डार तेजी से खत्म होता जा रहा है, ऊर्जा का मूल्य भी सातवें आसमान तक पहुँचने लगा है। इसलिये सारी दुनिया के विभिन्न शिल्पोद्योग अधिक से अधिक ऊर्जा की बचत करने के लिये हर सम्भव उपाय ढूँढ़ निकालने में संलग्न हैं।

भारत में जहाँ उच्चकोटि के लौह अयस्क भारी परिमाण में मौजूद हैं, वहाँ उसे लोहे का रूप देने के लिये कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं। इस संदर्भ में देश के कच्चे मालों को बचाने वाला संरक्षण कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक है। और इसलिये इस्पात कारखाने में ऊर्जा-प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की ज़रूरत नहीं है।

TISTECH
ENERGY

वास्तव में टाटा स्टील तकनीक या टिस्टेक इस क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

सिर्फ लौह निर्माण करने वाले जहाँ ६५ प्रतिशत ऊर्जा खर्च करते हैं वहाँ अधिक से अधिक ऊर्जा-संरक्षण निर्धारित करने के लिये विभिन्न उपायों का एक सिलसिला अपनाया गया।

कोक-अवन में बेहतर ताप नियंत्रण, ईंधन-हवा के अनुपात में उत्तम प्रबन्ध होने के कारण जहाँ कोक की क्वालिटी में उन्नति हुई, वहीं ऊर्जा में भारी बचत भी।

ब्लास्ट फर्नेस में वेरियेबल थ्रोट आर्मर और रोटेटिंग श्यूट् चालू होने से कोक के खर्च में भारी कमी आई। बेहतर कोक के उत्पादन, सिन्टर के अनुपात में वृद्धि तथा ब्लास्ट की उच्चतर तापमात्रा आदि से ऊर्जा बचत में उल्लेखनीय मदद मिली।

NSEL
ARCTIC OCEAN
PACIFIC

आज, बढ़िया कोक उत्पादन के लिये स्टैम्प चार्जिंग तकनीक का प्रयोग तथा सिन्टर की तैयारी में ब्लू डस्ट के उपयोग में उन्नत प्रक्रिया का मतलब प्रासंगिक ऊर्जा प्रबन्ध कार्यक्रम में टिस्टेक की शानदार सफलता। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत खनन-कार्य से लेकर इस्पात निर्माण और उसकी अन्य प्रक्रिया शामिल है। ऐसा कार्यक्रम जिसमें टाटा स्टील का हर कामगार संलग्न है। ऐसा कार्यक्रम जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र के राजस्व में करोड़ों रुपये भरेगा।

सिर्फ मशीन और प्रक्रिया ही नहीं, टिस्टेक, चेतना पर भी असर करता है। लम्बी-अवधि ऊर्जा प्रबन्ध नीति को सफल बनाने के लिये लोगों के मन को भी असल विषयों के बारे में सचेत रखना चाहिये। आज, कोलियरी में काम करने वाले सिर्फ 'टन' की ही बात नहीं करते, वे 'ऊर्जा मूल्य' और 'राख की मात्रा' जैसे विषयों की भी चर्चा करते पाये जाते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेसों के कर्मी 'कैलोरी' के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, दूसरे शब्दों में एक सम्पूर्ण नई भावना टाटा स्टील में काम कर रही है।

टिस्टेक ऊर्जा, स्टील प्लान्टों के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक मार्गदर्शक प्रयास—जिसका लक्ष्य है एक प्रासंगिक तकनीक का उद्भावन, एक आधुनिक प्रगतिशील धारणा का प्रसारण। आने वाले कल के प्रयोजन को न भूल कर आज के जमाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के वायदों का एक और नाम है—टिस्टेक!

- **गरम ब्लास्ट के तापमान में १००° सेन्टीग्रेड वृद्धि के दौरान कोक के उपयोग में कटौती।**
- **केवल लोहा निर्माण में ऊर्जा के रूप में १०० करोड़ रुपये की बचत।**
- **कोक की दर में कमी के लिये रोटेटिंग श्यूट् और वेरियेबल थ्रोट आर्मर चालू।**
- **ब्लास्ट फर्नेसों में बढ़िया कोक प्रयोग के लिये स्टैम्प चार्जिंग तकनीक जारी।**

टाटा स्टील

सबसे पहले सबसे आगे

एक ब्लास्ट फर्नेस में रोटेटिंग श्यूट्

ब्लास्ट फर्नेस की एक बाहरी झलक

एक किलो सागर स्किम्ड मिल्क पाउडर आपको देता है
साढ़े दस लीटर स्किम्ड मिल्क.
इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे यूं ही पीना पसंद करेंगे.
या फिर आप इससे गुलाबजामुन, आइसक्रीम, दही,
खीर, रसगुल्ला, कस्टर्ड, मिल्कशेक भी बना सकते हैं.
और हां, चाय और कॉफ़ी भी.
सागर. दूध का सागर.

SAGAR
SKIMMED
MILK POWDER
SPRAY DRIED

सागर
स्किम्ड मिल्क
पाउडर
५०० ग्राम के
पैक में
उपलब्ध.

बिक्री व्यवस्था - गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आणंद, गुजरात. OPERATION FLOOD

ASP-SSMP-357/88 HIN

बोफोर्स की नयी गूंज

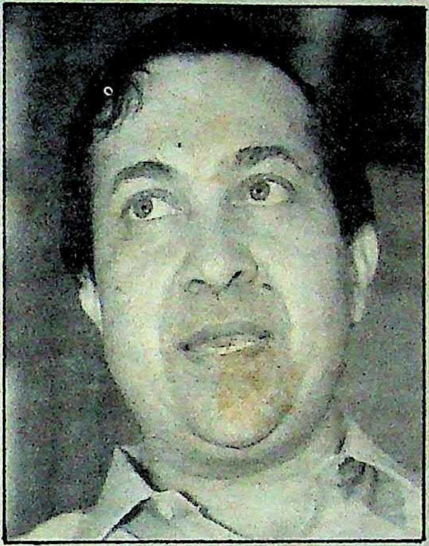

बढ़ता संदेह: एन राम

रक्षामंत्री कृष्ण चंद्र पंत की 'खुली बगावत' के झटके से प्रधानमंत्री राजीव गांधी उबर भी न सके थे कि चौबीस घंटे के भीतर ही राष्ट्र के १० प्रमुख दैनिकों ने बोफोर्स दलाली प्रकरण की अगली किस्त प्रकाशित कर स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सीधी शिरकत के नये धमाकेदार प्रमाण प्रस्तुत कर दिये। दस्तावेजों के प्रकाशित होने की तिथि और सूचना 'हिंदू' के सहयोगी संपादक एन राम ने अपनी विदेश यात्रा से लौटने के शीघ्र बाद ही दे दी थी। सोमवार ३० अक्तूबर की रात ९ बजे छपते डाक संस्करणों से निकली खबरें राजधानी में दावानल की तरह फैलती गयीं। सबसे विस्फोटक सूचना गांधी ट्रस्ट (ई) का ब्यौरेवार उल्लेख था।

अगली सुबह प्रकाशित दस्तावेजों में बोफोर्स कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक मार्टिन आर्दबो की डायरी की २ जुलाई '८७ की ये घातक प्रविष्टियां थीं: जिनेवा में मायो एसोसिएट्स के कार्यालय में एई सर्विसेज लि० के माइल्स स्टार की बातचीत में उन्हें यह सूचना मिली, "बाब ने गांधी ट्रस्ट (ई) के वकील से बातचीत की है।"

आर्दबो की इस हस्तलिखित एक पंक्ति से एक ओर यदि स्विट्जरलैंड में गांधी ट्रस्ट होने का खुलासा हुआ, तो दूसरी ओर इसने भारत सरकार और राजीव गांधी के उन सभी दावों को भी झुठला दिया, जिनका आशय था कि इस प्रविष्टि के तीन माह आगे तक उन्हें एई सर्विसेज के विषय में कोई जानकारी ही न थी। आरोप है कि ऐसा बयान जारी करते समय प्रधानमंत्री ढंकने-मूंदने के प्रयास में जानबूझकर गलतबयानी कर रहे थे।

मामला मात्र कथित गलतबयानी तक ही सीमित नहीं था। स्विस ट्रस्ट के वकील और एई सर्विसेज के निर्देशकों के बीच हुई गुप्त बैठक के दो दिन बाद राजीव गांधी ने आदेश देकर बोफोर्स अधिकारियों की उस भारत यात्रा को भी तुरंत रद्द किया, जिसमें वे बोफोर्स कमीशन के तथ्यों की जानकारी देने आ रहे थे। उल्लेखनीय है कि हाल में प्रकाशित एक साक्षात्कार में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी ने इसका उल्लेख करते हुए दौरे को रद्द किये जाने को तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सखा अरुण सिंह के इस्तीफे का कारण बताया था।

प्रकाशित दस्तावेजों में चार लोगों का सीधा जिक्र है। एक हिंदूजा, दो विन चड्ढा, तीन बाब विल्सन और चौथा गांधी ट्रस्ट (ई) का वकील। यद्यपि अंतिम व्यक्ति की शिनाख्त सीधे-सीधे नहीं दी गयी है, किंतु पिछले रहस्योद्घाटन के दौरान एन राम और चित्रा सुब्रह्मण्यम ने 'इतालवी संबंधों' का स्पष्ट उल्लेख किया था। अतः प्रश्न उठता है कि क्या यह व्यक्ति वही इतालवी संपर्क है? यही नहीं, एन राम और चित्रा सुब्रह्मण्यम ने इस बार किये अपने नये रहस्योद्घाटन के अन्त में एक बार फिर यह संकेत दिया है कि इन तमाम तथ्यों के अलावा 'स्वतंत्र रूप' से भी उनके पास सबूत हैं जो समस्त घोटाले में राजीव गांधी का सीधा हाथ साबित करते हैं।

> **सर्वाधिक हलचल और प्रभाव कांग्रेसी खेमे में दिखायी पड़ा। यद्यपि संसदीय दल के सचिव पीएन सुकुल का कहना था कि ये सब मात्र चुनावी हथकंडे हैं, जिनका मतदाताओं पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। किंतु आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हतोत्साह किसी से छिपा नहीं रहा।**

यद्यपि बोफोर्स प्रकरण की शुरुआत से ही राजीव गांधी संदेह के घेरे में बने रहे हैं, पर इस रहस्योद्घाटन ने संदेह को सबूत में परिवर्तित कर सबको हतप्रभ कर दिया है। तीन घंटे के भीतर ही भाजपा ने इसी नये रहस्योद्घाटन को लेकर विशेष बैठक बुलायी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यदि राष्ट्रपति को ज्ञापन दे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की, तो के आर मल्कानी ने राजीव गांधी का पासपोर्ट ही जब्त करने की मांग कर दी। उधर भाकपा ने अपनी बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें तय किया गया कि अब सीधे जनता ही अपनी अदालत में सजा सुनायेगी।

सर्वाधिक हलचल और प्रभाव कांग्रेसी खेमे में दिखायी पड़ा। यद्यपि संसदीय दल के सचिव पीएन सुकुल का कहना था कि ये सब मात्र चुनावी हथकंडे हैं, जिनका मतदाताओं पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। किंतु आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हतोत्साह किसी से छिपा नहीं रहा। एक पूर्व कांग्रेसी सांसद ने 'माया' से कहा, "हम किस मुंह से जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे।" गिरते मनोबल का आलम कुछ ऐसा था कि बहुतों ने पंत की बगावत के पीछे इन दस्तावेजों की पूर्व जानकारी का हाथ देखा। उनके साथ अजीत प्रताप सिंह (उप्र) के भी चुनावी मैदान से बाहर जाने के समाचार ने यह आशंका बलवती की कि कांग्रेस में बोफोर्स तोप के नये गोलों से भगदड़ मच सकती है। इसका एक संकेत तब और मिला जब बोफोर्स के दस्तावेज छपने के थोड़ी देर बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पी नरसिम्हाराव ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भेंट की। जानकार सूत्रों के अनुसार राव ने राजीव गांधी से मांग की है कि वे अखबारों में छपी इस खबर का खंडन करें। राजधानी के राजनीतिक पर्यवेक्षक इसका सीधा एक ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पंत अकेले नहीं हैं। अब एक के बाद एक यदि और मंत्री उंगली उठायें, तो आश्चर्य नहीं होगा। इन दस्तावेजों के छपने के बाद प्रधानमंत्री सचिवालय के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 'गांधी ट्रस्ट' से कोई संबंध नहीं है तथा इस संबंध में प्रकाशित दस्तावेज फर्जी हैं। बहरहाल चुनाव के समय तक बोफोर्स तोपें निरंतर गूंजती रहेंगी—इसके स्पष्ट संकेत हैं।

—रंजना कक्कड़, पुनीत टंडन,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव,

चुनावी युद्ध के लिए फिल्मी हथियार

आखिर 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' के जरिये चुनावी युद्ध लड़ने की एनटी रामाराव की योजना, दूरदर्शन पर दसरि नारायण राव के सीरियल 'विश्वामित्र' के प्रसारित हो जाने तथा राजीव गांधी द्वारा निर्धारित समय से पहले ही चुनाव कराये जाने की घोषणा के कारण, धूमिल पड़ गयी। उन्होंने भी 'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र' का निर्माण बीच में ही रोक दिया, ताकि चुनावी-प्रचार के लिए नयी रणनीति तैयार कर सकें। अब उनकी यह बहुप्रतीक्षित फिल्म भविष्य में पूरी होकर परदे का मुंह देख भी सकेगी या नहीं, नहीं कहा जा सकता।

अंधेरगर्दी तथा कर्मयोद्धा : राज बब्बर ने आम चुनाव को ध्यान में रखकर दो फिल्मों का निर्माण शुरू कराया था—'अंधेरगर्दी' तथा 'कर्मयोद्धा'। वे इसे दिसंबर में आम चुनाव से १५ दिन पहले रिलीज करना चाहते थे, ताकि ये दोनों फिल्में पूरे दो सप्ताह तक सिनेमा हालों में लगी रहें और दर्शकों के मन में राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाती रहें। लेकिन चुनाव तिथि दिसंबर के बजाय नवंबर में पड़ने के कारण अब उन्हें कोई वितरक नहीं मिल पा रहा है, जो इसे मतदान से एक पखवारे पहले सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर सके। लेकिन राज बब्बर किसी भी शर्त पर इन्हें १० नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि दो सप्ताह तक ये फिल्में आम मतदाताओं को प्रभावित कर सकें।

आम चुनाव को ध्यान में रखकर बनी इन फिल्मों के निर्माण की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने 'सच' (बाद में 'सत्यम', फिर 'मैं आजाद हूं') से की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू, एक्सप्रेस ग्रुप, राम जेठमलानी आदि द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों का जवाब वे फिल्मी स्टाइल में देना चाहते थे। लोकसभा से त्यागपत्र देने के बाद वे एक प्रेस कांफ्रेंस में वक्तव्य देकर अपनी बात साफ करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली दरबार में अमिताभ विरोधी गुट ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, तो उन्होंने 'सच' का सहारा लिया। उन्होंने प्रख्यात फिल्म लेखक जावेद (सलीम-जावेद की टूटी जोड़ी) से इस विषय पर कथा-पटकथा लिखवायी, जिसमें समाज के खलनायक (अमिताभ के राजनीतिक दुश्मन) उन पर तरह-तरह के गलत आरोप लगाकर, अपमान का कीचड़ फेंककर तथा अपने चक्रव्यूह में फंसाकर उन पर चौतरफा हमला करते हैं और अंततः उन्हें मार डालते हैं। इस फिल्म-निर्माण से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के अनुसार, ''कुछ-कुछ ऐसा ही अमिताभ की राजनीतिक जिंदगी में भी हुआ। 'मैं आजाद हूं' इसी राजनीतिक हत्या की साजिश की फिल्म है, जो आम जनता की आंखें खोल देगी।''

मैं आजाद हूं : 'मैं आजाद हूं' की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफे और प्रेस वक्तव्य न दे पाने के तुरंत बाद की थी और उनकी योजना थी कि इसे एक महीने मे पूरी कर इसे रिलीज कर दें। लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें इसे आम चुनाव के दौरान रिलीज कराने की सलाह दी, क्योंकि उनके राजनीतिक दुश्मनों को जवाब देने का सही मौका होता। अमिताभ को उनकी सलाह ठीक लगी। उन्होंने अपनी आम फिल्मों की 'टेरीटरी प्राइस' (६५ से ७५ लाख रुपए प्रति वितरण क्षेत्र) एकदम से घटाकर साढ़े आठ लाख रुपए इस शर्त के साथ कर दी कि वितरक एक साथ अपने क्षेत्र के छोटे शहरों, कस्बाई सिनेमाघरों में भी इसे रिलीज करेंगे।

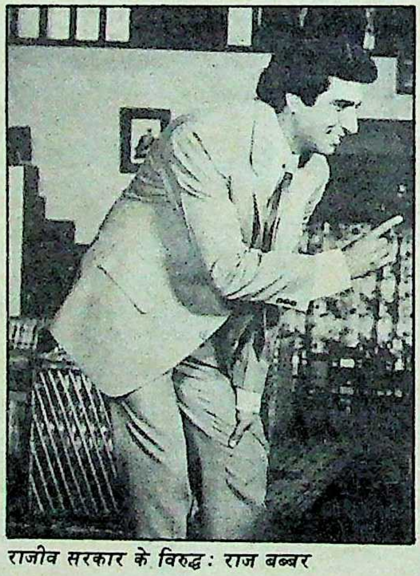

राजीव सरकार के विरुद्ध : राज बब्बर

राजीव गांधी पर फिल्म : राज कपूर पर एक वृत्तचित्र बनाकर बंबई के फिल्म्स डिवीजन को संकट में डाल देनेवाली अभिनेत्री-निर्माता-निर्देशिका सिमी गरेवाल ने भी कम लंबी छलांग नहीं लगायी। लता मंगेशकर पर प्रस्तावित अपनी फिल्म को बस्ते में बंद कर उन्होंने सीधे राजीव गांधी पर फिल्म बना डाली। सिमी इस फिल्म को पहले अमरीकी टीवी तथा बीबीसी नेटवर्क पर रिलीज करना चाहती थीं, बाद में भारतीय दूरदर्शन पर। लेकिन दरबार के कुछ अहलकारों की सलाह पर उन्होंने अपनी योजना बदल दी। अब उनकी यह फिल्म आम चुनाव के दौरान गांव-गांव तक दिखलायी जायेगी। फिल्म के बारे में सिमी ने 'माया' को बतलाया, ''यह एक तरह से ऐतिहासिक फिल्म है राजीव गांधी पर, जिसे लोग अगले चालीस वर्षों तक याद रखेंगे। यह आर्काइव्ज में रखने लायक फिल्म है। राजीव गांधी ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। लोग उनके व्यक्तित्व के जादू से दशकों प्रभावित रहेंगे। फिल्म का प्रथम भाग (४५ मिनट) पूर्णतया राजनीतिक है, शेष भाग (४५ मिनट) पूर्णतया व्यक्तिगत। मैंने उनकी शख्सीयत के बहुत से ऐसे पहलुओं को फिल्माया है, जिसे देखकर लोग

राजनीतिक दुश्मनों पर हमला : फिल्म 'मैं आजाद हूं'

में अमिताभ बच्चन

चौंकेंगे। लोग उनके जीवन मूल्यों, शख्सीयत की विशेषताओं से प्रभावित होंगे और उन्हें सही ढंग से जान पायेंगे।"

सिमी यह दावा तो नहीं करती हैं, लेकिन यह जरूर मानती हैं कि प्रतिपक्षी दलों ने राजीव की इमेज को जिस तरह से तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की है, उसे यह फिल्म ठीक करने में काफी हद तक सहायक होगी।

सुनील दत्त ने भी चुनाव को ध्यान में रखकर एक फिल्म का निर्माण शुरू किया था, जिसका मुख्य विषय था—राष्ट्रीय एकता तथा दहेज की समस्या, जिसमें नायक (सुनील दत्त) की बेटी को ससुराल वाले जला देते हैं। सुनील दत्त को उम्मीद थी कि उनकी फिल्म नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पूरी होकर रिलीज हो जायेगी। लेकिन २२-२४ नवंबर को चुनाव की घोषणा ने उनके इस फिल्मी हथियार को भी बेकार साबित कर दिया। वरना सुनील दत्त को पूरी उम्मीद थी कि उनकी यह फिल्म मतदाताओं को उनके तथा पार्टी के प्रति आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

धर्मशक्ति से आशाएं : नवंबर में चुनाव के ऐलान ने बीआर चोपड़ा की फिल्म 'धर्म शक्ति' को भी प्रभावित किया। फिल्म के नायक मिथुन चक्रवर्ती को उम्मीद थी कि 'धर्मशक्ति' में निभाया उनका संघर्षरत प्रगतिशील युवक का किरदार मार्क्सवादी राज्यों की जनता को काफी हद तक प्रभावित करेगा। फिल्म में अपने किरदार की चर्चा करते समय एक बार उन्होंने कहा था, "हालांकि यह फिल्म न तो राजनीतिक है और न ही राजनीति से प्रभावित। लेकिन फिल्म में मैंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हंसिया उठाया है। यह हंसिया कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक है जो आंदोलन को एक नयी शक्ति प्रदान करता है।"

मिथुन पहले नक्सली रह चुके हैं और पिछले आम चुनाव तथा उप चुनावों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पार्टी के लिए तन-मन-धन से कार्य किया था। यह दूसरी बात है कि शिवसेना के दबाव पर उन्होंने शिवसेना का भी पिछले उपचुनाव में प्रचार किया था।

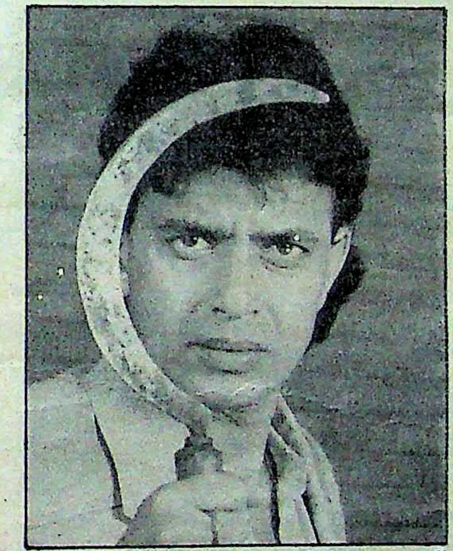

वामपंथी तेवर : फिल्म 'धर्मशक्ति' में मिथुन चक्रवर्ती

शबाना की उम्मीद : अमिताभ की ही तरह शबाना आजमी भी 'मैं आजाद हूं' से काफी आशान्वित हैं। पत्रकारों से नाक-भौं सिकोड़नेवाली शबाना ने इसमें एक पत्रकार की भूमिका निभायी है और इस भूमिका को वे पत्रकारों के लिए सही आचार संहिता मानती हैं। मार्क्सवादी पार्टी तथा जनता दल उन्हें हरकिशन लाल भगत के मुकाबले अथवा आजमगढ़ से लड़ाने के इच्छुक भी थे। शबाना ने अपनी अमरीका यात्रा के दौरान कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोग्रेसिव स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित बैठक में कहा था, "मैंने फिलहाल चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं बनायी है, लेकिन इतना अवश्य है कि राजीव गांधी की सरकार को हटाये बिना भारत में किसी भी प्रकार के सुधार की कोई संभावना नही रह गयी है।"

राम को निराशा : इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करनेवाले 'रामायण' सीरियल में राम उर्फ अरुण गोविल ने चुनाव को मद्देनजर रखकर ही 'मशाल' सीरियल का निर्माण किया था। दूरदर्शन ने चुनाव-तिथि की घोषणा के बाद १६ अक्तूबर से हर सोमवार को 'मशाल' के प्रसारण की योजना तो बनायी थी, लेकिन इसे जगजाहिर नहीं किया था, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए मंगलवार अथवा शनिवार चाहते थे। इसीलिए सात एपीसोड पूरा कर चुकने के बावजूद उन्होंने 'मशाल' प्रसारण के लिए नहीं दिया और इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्री से रूबरू बात करने का निश्चय किया।

प्रचार-फिल्में : लेकिन इन फिल्मों से भी महत्वपूर्ण हैं, वे वीडियो तथा दूसरी प्रचार फिल्में जो बंबई, हैदराबाद, मद्रास तथा दिल्ली में बन रही हैं। आत्माराम द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह पर निर्मित फिल्म को जनता दल ने चुनाव के दौरान जगह-जगह दिखलाने की योजना बनायी है। कांग्रेस ने लगभग ३०० करोड़ रुपए की लागत से प्रचार-फिल्मों तथा आडियो-वीडियो कैसेट का निर्माण कराया है। राजीव परिवार के खास चारण जगदीश पीयूष तो पूरी फिल्म यूनिट लेकर जगह-जगह घूमते फिर रहे हैं। बंबई के बहुत सारे नये-पुराने फिल्मकारों को इसके लिए अनुबंधित किया गया है। अधिकांश रिकार्डिंग डबिंग तथा एडिटिंग थियेटर इसके लिए इस तरह बुक कर लिये गये हैं कि दूसरी फिल्मों, सीरियलों तथा वीडियो फिल्मों का निर्माण ठप-सा पड़ गया है।

ऐसी ही प्रचारात्मक फिल्मों में एक सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। उस फिल्में में विपक्ष के सात दिग्गज नेताओं (विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी देवीलाल, एनटी रामाराव, अटल बिहारी वाजपेयी, अजीत सिंह, रामकृष्ण हेगड़े तथा चंद्रशेखर) की मिमिक्री की गयी है। कलाकार इन नेताओं के कार्टून-मास्क पहन कर जनता के बीच जाते हैं। इन नेताओं के नाम भी इनके नाम से मिलते-जुलते रखे गये है मसलन वीपी सिंह को सीपी सिंह, देवीलाल को लेवीलाल, अजीत को नजीत, अटल बिहारी को नकल बिहारी, हेगड़े को बेगड़े, चंद्रशेखर को अंदरशेखर, एनटीआर को एनसीआर नाम से पुकारा गया है। सात नेताओं की इस सूची में पहले दो और नाम थे—तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, लेकिन ऐन मौके पर ये नाम निकाल दिये गये।

—रवींद्र श्रीवास्तव

मीडिया पर कांग्रेस आज भी हावी है

इस चुनाव में कांग्रेस अपने प्रचार कार्य पर अभूतपूर्व मात्रा में धनराशि खर्च कर रही है। खर्च का अनुमान २०० करोड़ से लेकर ३०० करोड़ तक लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टीवी-रेडियो के जरिये परोक्ष रूप से कांग्रेस का प्रचार जारी है ही। क्या यह प्रचार कार्य कांग्रेस को चुनाव जिताने में कारगर सिद्ध हो पायेगा?

कांग्रेस दर्शन : टीवी पर कांग्रेस का परोक्ष प्रचार

"आपका घर देख सकते हैं?"
"खेती करते हो?"
"जमीन कितनी है?"
"मिट्टी का तेल मिलता है?"
"हमारी चिट्ठी मिली?"
"कैसा लगा?"

ग्रामीणों की टोली से चुनाव घोषणा के बाद पूछे गये उपर्युक्त प्रश्न दूरदर्शन की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन की खबर बन गये क्योंकि प्रश्नकर्ता कोई और नही, स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसलिए और भी क्योंकि राजीव के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री कमलाकांत तिवारी का मानना है, "प्रधानमंत्री का हर वाक्य समाचार होता है।" कदाचित इसी मानसिकता के तहत मौजूदा चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की गरीब समर्थक छवि को दूरदर्शन के माध्यम से ८० प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचाना-परोसना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का परम लक्ष्य हो गया है।

कांग्रेसी तैयारी : इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सात समुद्र पार तक की खाक छानी गयी है। एक उच्चाधिकारी ने 'माया' को बताया कि लंदन स्थित टेलीविजन पत्रकार करन थापर की दूरदर्शन ने विशेष स्थायी सेवा ग्रहण की है, जिससे कमलाकांत तिवारी की अगुवाई में दूरदर्शन की विश्वसनीयता-प्रामाणिकता पर लगे धब्बे को धोया-चमकाया जा सकें। किंतु थापर के अभियान की एक चाल चुनाव आयोग की तीखी नजर से मात खा गयी है। उल्लेखनीय है कि थापर ने तीन केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साक्षात्कारों की एक शृंखला तैयार की थी, जिसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखकर स्वयं १० अक्तूबर को पास किया था। इन साक्षात्कारों को १६ अक्तूबर से दूरदर्शन पर दिखाना तय था। किंतु उसके पूर्व ही चुनाव घोषित हो गये और थापर को चुनाव आयोग का निर्देश मिला कि वे उन साक्षात्कारों का प्रसारण नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि चुनाव की अवधि के प्रसारण के विषय में दूरदर्शन ने स्वयं १९८७ में अपना एक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किया था, जिसके 'मौजूदा मामलों' शीर्षक में कहा गया है, "चुनाव पूर्व सप्ताहों के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रमों को उत्तरदायित्व की भावना और उच्चस्तरीय निष्पक्षता से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे किसी राजनीतिक पार्टी को शिकायत न हो।"

वैसे जहां तक कांग्रेस द्वारा दूरदर्शन के इस्तेमाल की बात है, आम धारणा यही है कि भले ही चुनाव में कांग्रेस खुलकर दूरदर्शन का उपयोग न करे, फिर भी परोक्ष रूप से मीडिया द्वारा उसका प्रचार होता ही रहेगा। इस संबंध में 'उल्का' विज्ञापन एजेंसी के एक अधिकारी ने 'माया' से कहा, "कांग्रेस दूरदर्शन पर सीधे प्रचार न करके भी अपना मकसद पूरा कर रही है। जैसे रविवार को 'महाभारत' के पहले अग्नि का प्रक्षेपण दिखाकर ऐसा ढोल पीटा जाता है, मानो अग्नि प्रक्षेपण राजीव गांधी की व्यक्तिगत उपलब्धि हो। ऐसे अनेक अन्य अवसर तलाशे गये हैं। मसलन पिछले ५ वर्षों में सरकार की औद्योगिक-आर्थिक प्रगति, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आदि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का भजन-कीर्तन दूरदर्शन पर जोर-शोर से होता रहेगा।"

फिल्मों पर जोर : सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रचार का सबसे सशक्त हथियार 'मां' नामक एक फिल्म है, जिसे श्रीमती गांधी की हत्या के पूर्व तैयार किया गया था। फिल्म में श्रीमती गांधी मातृत्व भाव से कुछ ऐसे सवालों का जवाब देती हैं जैसे, 'राजीव ने आपको कोई तकलीफ दी है' आदि। यह फिल्म १९८४ की बची-खुची सहानुभूति लहर को भुनाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथकंडा है। देशव्यापी प्रदर्शन के लिए इस फिल्म

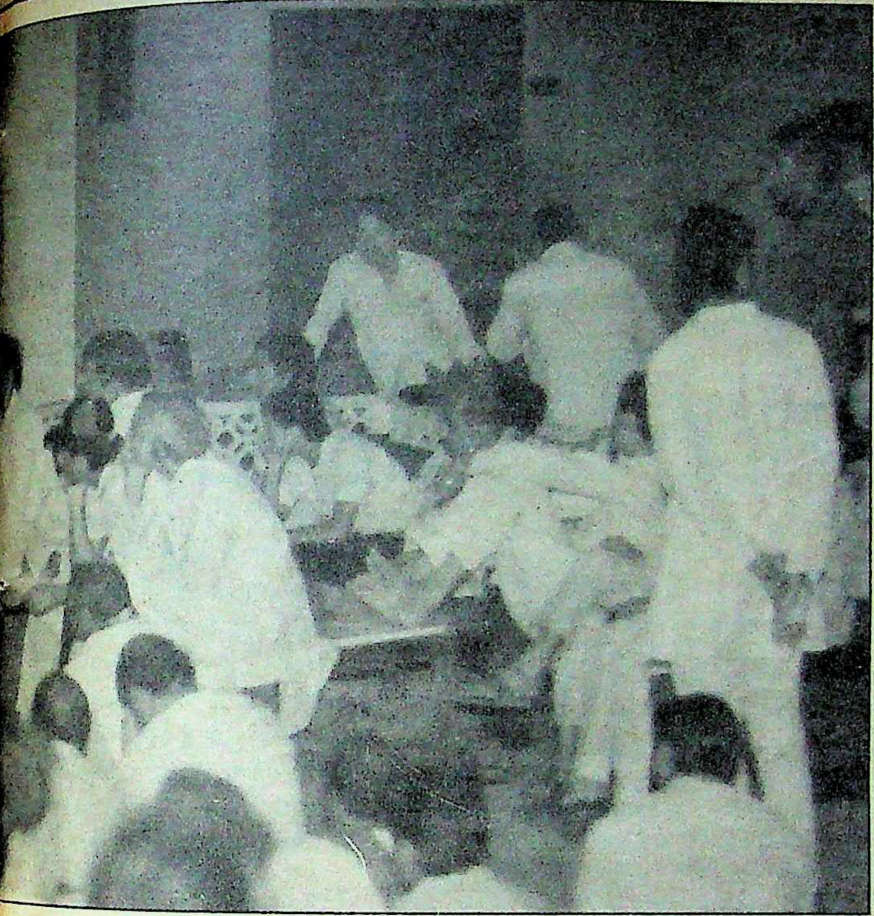

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 'डब' कराया गया है। इसी प्रकार १४ नवंबर के नेहरू शताब्दी समारोह दिवस के सिलसिले में बनी विभिन्न फिल्मों को 'चुनावी महाभारत' में शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की भी कांग्रेस की रणनीति है। इसके जरिए नेहरू परिवार और उसकी उपलब्धियों का जोरशोर से बखान किया जायेगा। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नवंबर के दूसरे पखवारे में चुनाव कराने का इरादा राजीव गांधी ने अपने नाना पंडित नेहरू व मां श्रीमती गांधी के जन्म दिवसों को ध्यान में रखकर ही बनाया, ताकि इन अवसरों का अधिकाधिक राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

इसी तरह पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक, जो राज्यसभा में आवश्यक बहुमत के अभाव में पास नहीं हुए, कांग्रेस के दूरदर्शन प्रचार अभियान के मुख्य अंग हैं। 'कृषि दर्शन' जैसे कार्यक्रमों में 'जनशक्ति' के लिए संघर्षरत कांग्रेस और पंचायती बिल को विफल करने वाले विपक्ष को मनचाहा रंग दिये जाने की पूरी कोशिश है, तो 'युवाओं के लिए' कार्यक्रम में १८ वर्ष के मतदाताओं को मताधिकार देने का ढिंढोरा पीटने का प्रयास भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

शासक दल द्वारा चुनावों में सरकारी मीडिया के दुरुपयोग का जिक्र जब 'माया' ने भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से किया, तो दूरदर्शन के मुकाबले अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा, "हम इसकी काट के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम हम इसे मतदाताओं के सामने उजागर कर इस माध्यम की विश्वसनीयता पर प्रहार करेंगे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य उपलब्ध माध्यमों से हम अधिकाधिक प्रचार करेंगे। इसीलिए हमने आडियो-वीडियो कैसेट भी तैयार कराये हैं।"

दूरदर्शन का प्रयोग: विपक्ष चाहे जो भी कहे अथवा करे, किंतु यह निर्विवाद है कि चुनावों में सरकारी मीडिया के दो सूत्री प्रयोग की रणनीति कांग्रेस ने बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। उदाहरणार्थ कांग्रेस ने लंबे समय की रणनीति के तहत लोक सेवा संचार द्वारा तैयार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रचार के लिए 'मेरा भारत महान' और 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिये थे। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य था, छोटे परदे पर देश प्रेम, धर्म निरपेक्षता और एकता की भावनाओं का प्रचार। इसी के साथ शुरू हुआ था जनसभाओं व संसद में प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी दलों-नेताओं को देशद्रोही, पृथकतावादी और सांप्रदायिक करार देकर अपने अनुकूल जनमानस तैयार करने का अभियान। मजे की बात यह है कि दूरदर्शन द्वारा 'रामायण' और 'महाभारत' सीरियलों से धार्मिक पुनर्जागरण को पहले तो हवा देकर कांग्रेसी सरकार ने रामशिला पूजन का बीजारोपण किया और फिर सांप्रदायिकता को जुबानी विरोध से

एनटीआर का जवाब: 'विश्वामित्र' धारावाहिक

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

राजनीति के चौपड़ पर किसका खेल चौपट

माया... सच के दरवाज़े की चौखट

राजनीति के चौपड़ पर किसका पासा उलटा पड़ता है? किसका सीधा? कौन उखड़ता है? कौन जड़ पकड़ता है? कौन से बादल गरजते हैं, कौन से बरसते हैं? कौन सिक्का खोटा है, कौन चना थोथा है... यह केवल बातों की चाट नहीं, बल्कि सचाई की थाह तक पहुंच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है-माया।

आज की बात बनती है कल का इतिहास और माया अपना राष्ट्रीय दायित्व समझकर निष्पक्ष व निडर भाव से पाठकों को सचाई से अवगत कराती है। राजनीति के दांवपेच हों या समाज के कुचक्र सभी के लिए दुधारी तलवार, जिसका वार घातक के लिए घाव और आहत के लिए उपचार। माया, जिसने आज के भारत के लिए हिन्दी का परचम लहराया।

६० बरसों के अनुभव में पली, भारतीय संस्कारों में ढली...माया। हिन्दी के पाठकों की एकमात्र ऐसी समाचार पत्रिका जो हिन्दी में सोचती है और हिन्दी में बोलती है, क्योंकि हिन्दी ही आपकी और हमारी भाषा है।

माया... वह खबर देती है, जिसकी किसी को खबर नहीं होती।

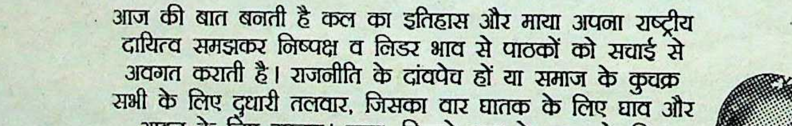

जिसमें आज का भारत सिमट आया

Karishma/MAYA/10/2418 HI

दबाने की रणनीति छेड़ दी। इस संबंध में दिल्ली के एक कालेज के अध्यापक मोहन मिश्र ने 'माया' से कहा, "अब 'विश्वामित्र' के प्रसारण से न केवल क्षत्रिय राजा विश्वरत के बहाने वीपी सिंह पर हमला किया जा रहा है, बल्कि 'एक मजबूत केंद्र' की वकालत की जा रही है।"

सूत्रों के अनुसार दूसरी, फौरी रणनीति के तहत पिछले दरवाजे से प्रवेश की योजना बना 'सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे' की शैली कांग्रेस ने अपनायी है। दूरदर्शन पर प्रसारित होनेवाले समाचारों में क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, इसे रोजाना विस्तार से तय किया जा रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्री एचकेएल भगत और तिवारी को दरकिनार करके सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'क्या समाचार देना है और कैसे देना है, इसकी कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। इसमें करन थापर सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि आरके धवन, मणिशंकर अय्यर, आनंद शर्मा और डीपी त्रिपाठी की देखरेख में भी एक अभियान समिति गठित हुई है। अय्यर को जहां प्रधानमंत्री के भाषण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, वहीं अन्य तीनों चुनावी प्रचार-प्रसार के झंडाबरदार हैं।

काट के लिए तैयार : आडवाणी

भाकपा सचिव एम फारूकी ने शासक दल के मीडिया के बेजा इस्तेमाल की बात करते हुए 'माया' से कहा, "राजीव गांधी हरियाणा व तमिलनाडु के चुनावों में मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद मुंह की खा चुके हैं। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी, कांग्रेस शासित राज्यों में सांप्रदायिक दंगे, कानून-व्यवस्था की बदतर हालत और लोकतांत्रिक संस्थानों का एक के बाद एक हनन ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें दूरदर्शन अपने रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से दबा नहीं सकता।"

विपक्ष पीछे नहीं : बहरहाल, विपक्षी नेताओं के उपर्युक्त बयान से जहां यह स्पष्ट होता है कि चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए सबने कमर कस रखी है, वहीं यह बात भी उद्घाटित होती है कि शासक दल के ज़ादुई चिराग-दूरदर्शन-की काट के लिए विपक्ष के पास एकमात्र सहारा वीडियो फिल्में हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में इसका प्रथम सफल प्रयोग चौधरी देवीलाल ने किया था। दिल्ली स्थित जेके जैन वीडियो से दुबारा वीडियो फिल्में बनवाकर हरियगणा के गांव-गांव में उसे दिखाकर देवीलाल ने अपनी हाल की दिल्ली रैली में पर्याप्त भीड़ जुटायी थी। एक विपक्षी नेता के अनुसार, "हमने स्थानीय भाषाओं में वीडियो फिल्में तैयार करा ली हैं। इसका चुनाव अभियान में सीधा, धारदार प्रभाव पड़ेगा।" किंतु विपक्ष का यह दावा अधिक कारगर नहीं लगता, क्योंकि शासक दल कांग्रेस, स्वयं अपने चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए नाटक-नौटंकी के अलावा गीत-संगीत वाले हजारों आडियो-कैसेट और वीडियो फिल्में तैयार करा चुकी है।

जानकारों की सूचना के अनुसार कांग्रेस-इ ने प्रचार-प्रसार के जो साधन तैयार किये हैं, उनका मुकाबला कर पाना विपक्ष के बस की बात नहीं। यही नहीं, पर्यवेक्षकों का तो यह भी मानना है कि राजनीति के अपराधीकरण से चुनाव के हिंसक होने की जो संभावना बलवती हुई है सो तो है ही, आडियो-वीडियो कैसेट आदि के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोपों के जिस भयावह वातावरण की बात की जा रही है, वह भी आग में घी का ही काम करेगा।

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

कांग्रेस-इ ने प्रचार-प्रसार के जो साधन तैयार किये हैं, उनका मुकाबला कर पाना विपक्ष के बस की बात नहीं। यही नहीं, पर्यवेक्षकों का तो यह भी मानना है कि राजनीति के अपराधीकरण से चुनाव के हिंसक होने की जो संभावना बलवती हुई है सो तो है ही, आडियो-वीडियो कैसेट आदि के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोपों के जिस भयावह वातावरण की बात की जा रही है, वह भी आग में घी का ही काम करेगा।

मेगा प्रचार अभियान

कांग्रेस ने अपने 'मेगा' चुनाव प्रचार के लिए 'रीडिफ्यूजन' विज्ञापन एजेंसी को प्रमुख ठेका दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दून स्कूल के साथी ४२ वर्षीय अरुण नंदा इस एजेंसी के प्रबंध निदेशक हैं। उल्लेखनीय है कि १९८४ में भी २५ करोड़ की लागत से कांग्रेस का यादगार चुनावी प्रचार रीडिफ्यूजन ने ही किया था। इस बार वक्त, कम काम ज्यादा होने के कारण पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल से संबद्ध 'क्लेरियन' और उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की 'मुद्रा' एजेंसी की भी सेवाएं हासिल की हैं। सूत्रों के अनुसार महज पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन व पोस्टर युद्ध के लिए ७५ करोड़ के बजट की व्यवस्था कांग्रेस-इ ने की है।

अखबारी विज्ञापनों का सिलसिला गत २५ अक्तूबर से 'क्या भारत को इस स्वरूप में आप आखिरी बार देख रहे हैं' के नारे व भारत के क्षेत्रीय मानचित्र के साथ प्रारंभ हो गया है, जो ऐन चुनाव पूर्व तक लगभग नित्य जारी रहेगा। इसी के साथ समाचार पत्रों में सांप्रदायिकता विरोधी विज्ञापन भी प्रकाशित कराये जा रहे हैं। सांप्रदायिकता विरोधी इस विज्ञापन में नारे के रूप में यह लिखा जा रहा है, "क्या सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और अराजकता का जहरीला डंक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जायेगा?" हालांकि आम आदमी पर इस तरह के विज्ञापनों का कोई खास प्रभाव नहीं दिखायी पड़ रहा है, उलटे लोग इस तरह का सवाल पूछते फिर रहे हैं कि आखिर लगभग ४० वर्षों के कांग्रेसी शासन के बाद ऐसा क्या हो गया है जो भारत के टूट जाने की बात के सहारे कांग्रेस वोट मांगने को मजबूर हुई है।

एक जानकार सूत्र के अनुसार उपर्युक्त तीन विज्ञापन एजेंसियों के अलावा लगभग तमाम जानी-मानी एजेंसियों से भी इस 'पुण्य कार्य' में सहायता देकर अपनी भावी समृद्धि सुनिश्चित कराने की अपील की गयी है। पार्टी अपने कुल प्रचार अभियान में लगभग ३०० करोड़ रुपए स्वाहा कर रही है, ऐसा एक विपक्षी नेता का आरोप है। दीवारी पोस्टरों के कुछ चुनिंदा नारे इस प्रकार हैं: 'जन शक्ति की यही पुकार, राजीव गांधी फिर एक बार,' 'इंदिराजी का यह बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान', 'इंदिरा का संदेश आया, गद्दारों का करो सफाया, 'कांग्रेस की एक ही बात, सामंतों को दे दो मात।' उल्लेखनीय है कि १९८४ में श्रीमती गांधी के लिए बनी पूरी चुनाव प्रचार मुहिम का स्वर और शैली उनकी शहादत के बाद रातोरात बदल दी गयी थी। इस बार भी आकस्मिक चुनाव घोषणा से तैयारी के लिए गिने-चुने दिन ही उपलब्ध हैं। देखना है, करोड़ों की लागत का यह धुआंधार प्रचार अभियान क्या रंग लाता है?

◆

मतदाता का इम्तहान

ममता कालिया

देश में व्याप्त तमाम विषमताओं, समस्याओं और सवालों के बावजूद आम चुनाव की घोषणा से एक सनसनी और सरगर्मी पैदा हो गयी है। खादी की बिक्री यकायक बहुत बढ़ गयी, दर्जी धड़ाधड़ कुर्ते पाजामे और सदरी सीने लगे, रेलों में आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया और वे लोग जो कल तक अपने-अपने वातानुकूलित बंगलों में बैठ सत्ता के स्वप्न देखते हुए निंदासे थे, आज टिकट के लिए दिल्ली-लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। गाड़ियों की छटा निराली है। गाड़ियां खादी के कड़क कपड़ों में छिपी उम्मीदें भर-भर कर ढो रही हैं। उम्मीदवार अलग से पहचान में आ रहा है। दो-चार समर्थकों से घिरा, एक बेचैन चेहरा जो बार-बार घड़ी देखता है, रेल की रफ्तार को कोसता है, बार-बार टायलेट की तरफ जाता है और बातचीत में यह जताता है कि जनता की हर जरूरत का हल उसके पास है। उसके मन में गरीब आदमी के लिए यकायक इतना प्रेम उमड़ आया है कि वह उसे अपना माई-बाप कहने में गर्व का अनुभव करने लगा है। नाश्ते में उसे भुने चने अच्छे लगने लगे हैं, उसने खुश्क चपाती खानी शुरू कर दी है। जो गद्दीनशीं हैं, उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र की याद सताने लगी है। उन्हें अपनी जुबान की चाशनी पर भरोसा है।

इस सारी सरगर्मी में आम आदमी को एक तरह से काठ का उल्लू समझा जा रहा है। इन पांच सालों में जीवन जीने की घनघोर मशक्कत ने उसे कहां-कहां से काट खाया है, उसके जर्जर मकान की कितनी और ईंटें लोना खाई हैं, उसके कपडों में कितनी जगह और रफू के निशान बने हैं, यह सब देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। गति के नाम पर उसकी दुर्गति ही हुई है। इस बीच उसके पक्ष में सिर्फ एक काम हुआ है। आज का आम मतदाता वह नहीं है जो वह पांच साल पहले था। इस बीच उसने अपने आंसू और दूसरों की मुस्कान का स्वाद देख लिया है। वह पहले से ज्यादा यथार्थवादी, समझदार और परिपक्व हुआ है। चुनाव के समय उसे अपने महत्व का अच्छी तरह अहसास है। जिसने उसके लिए काम किया है, वोट वह उसी को देगा। असली बात है काम और इसी बिंदु पर आकर अनेक नेता बगलें झांक रहे हैं। यह बेवजह नहीं कि आज नेताओं में अपना चुनाव-क्षेत्र बदलने के लिए भीषण हड़कंप मचा हुआ है। हर आदमी एक सुरक्षित सीट चाहता है। कांग्रेसियों का वश चले, तो सब-के-सब मेढक से खड़े हो जायें। पांच साल वे अपने चुनाव-क्षेत्र से भागे-भागे फिरते रहे, अब क्या मुंह लेकर जनता के सामने जायें! अब तो ईश्वर-अल्ला दोनों उनके पक्ष में हों तभी, काम बनेगा।

हालत विपक्ष की भी यही है। जहां-जहां से विपक्ष जीता, थोड़ा बहुत शोर मचाने के अलावा कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सका। इलाहाबाद इसका सबसे करुण उदाहरण है। यहां के प्रबुद्ध और संवेदनशील मतदाता को पक्ष और विपक्ष दोनों ने ठगा है। जिस पर भी इसने विश्वास किया, उसी ने इसके साथ विश्वासघात किया। यही वजह है कि कभी कोई प्रत्याशी यहां से दो बार विजयी नहीं हुआ। इस क्षेत्र का चुनाव-परिणाम एक दिवसीय क्रिकेट मैच से कम उत्तेजनापूर्ण नहीं होगा। किसी एक का नाम यहां से अभिन्न रूप से नहीं जुड़ा है, जिस तरह इंदिरा गांधी और राजनारायण का रायबरेली से जुड़ा था अथवा जिस तरह राजीव गांधी का अमेठी से, नारायण दत्त तिवारी का काशीपुर से, राजेंद्र कुमारी बाजपेयी का सीतापुर से और असर पड़ा है? उसके लिए तरक्की का मतलब सिर्फ महंगाई संन्यास ही ले चुके, उन्हें जनता भले ही माफ कर दे, जो राजनीति में रहकर भी पलायनवादी साबित होंगे, उन्हें यहां की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आशंका यह है कि ऐसे प्रत्याशियों का और कहीं से जीतना भी कठिन सिद्ध होगा। जनता की नजर में चुनाव क्षेत्र बदलना दल बदलने से भी बड़ा गुनाह है।

> आज का आम मतदाता वह नहीं है जो वह पांच साल पहले था। इस बीच उसने अपने आंसू और दूसरों की मुस्कान का स्वाद देख लिया है। वह पहले से ज्यादा यथार्थवादी, समझदार और परिपक्व हुआ है। चुनाव के समय उसे अपने महत्व का अच्छी तरह अहसास है।

चुनावी दौरे शुरू होते ही विकास की लंबी-चौड़ी बातें होंगी और उपलब्धियों के आंकड़े पेश किये जायेंगे। लेकिन आम आदमी भाषण सुनने के बाद अपने घर की ओर जाते हुए यह जरूर सोचेगा कि इस विकास का उसके जीवन पर क्या असर पड़ा है? उसके लिए तरक्की का मतलब सिर्फ महंगाई भत्ते की एक-दो किस्त नहीं, बल्कि एक सरल और निष्कंटक जीवनचर्या है। सड़क पर सुरक्षा हो, घर में स्वतंत्रता, दुकान में राशन हो, नलों में पानी हो, स्विच दबाने से बिजली मिले, बच्चों को ठीक-ठीक तालीम मिले, यह तो है उसका निज का सपना। इसके बाद उसकी आंख देखती है राष्ट्र का सपना जिसमें एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्य हों, जहां प्रेरणा और गर्व के लिए उसे अनेक प्रकाश स्तंभ दिखायी देते रहें। वह यह भी चाहता है कि चुनावी लाभ के लिए देश को जाति और धर्मों में बांट कर निरीह लोगों के प्राण लेने की जो साजिशें हो रही हैं, उन पर भी अंकुश लगे।

जहां आम जनता के जेहन में मुल्क की बाबत इतनी साफ तस्वीर बनी हो, वहां नेताओं का गरीबी की रेखा, अमीरी की रेखा को लेकर लंबे-चौड़े वक्तव्य हांकना दिमागी कसरत के सिवा कुछ नहीं है। जनता को यह लगने लगा है कि ये रेखाएं अर्थशास्त्र से नहीं, राजनीतिशास्त्र से अपना अस्तित्व पाती रही हैं। गरीबी की रेखा को हर बार कुछ और नीचा कर कह दो कि अब और भी कम लोग गरीबी की रेखा के नीचे बचे हैं अथवा अमीरी की रेखा को थोड़ा-थोड़ा, नामालूम तरीके से ऊपर उठाते जाओ और कहो कि सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरणागत हैं, तो यह चतुराई सबकी समझ में आती है। देखना यह है इन समस्त चतुराइयों के बीच मतदाता अपने नीर-क्षीर विवेक का परिचय किस प्रकार देता है। ◆

अब नई पैकिंग में

अशोक मसाले

स्वाद व सुगंध में बेजोड़

स्पेशल मसाले : गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला, जलजीरा, दाल मसाला, रायता मसाला, हाजमी, सांभर मसाला, दम आलू मसाला, चना मसाला, दही बड़ा मसाला, चाट मसाला, चटनी पुदीना, किचन कुक, छोला मसाला, दूध मसाला, मुड़ी मसाला, चाय मसाला, पावभाजी मसाला।

पिसे मसाले : हल्दी, धनियां, मिर्चा, खटाई, जीरा भुना पाउडर, काश्मीरी मिर्च, कालीमिर्च

खड़े मसाले : जीरा, सौंफ मोटी, मेथी, राई, कलौंजी, सौंफ महीन, लाही, अजवाइन, कसूरी मेथी

अन्य : पापड़, हवन सामग्री, बीच साल्ट,

AGMARK
CURRY POWDER
GRADE STANDARD
Ashok
Garam masala
IODIZED
Beach
FREE FLOWING
SALT
Ashok
CHAT
MASALA

अशोक
करी पाउडर
सब्जी मसाला

अशोक
दम आलू
मसाला

अशोक
चना
मसाला
करी पाउडर

अशोक
करी पाउडर
मीट मसाला

उत्तर प्रदेश के बाहर वितरक/स्टॉकिस्ट बनने हेतु सम्पर्क करें

मुख्य वितरक

अशोक सेल्स कं. प्रा. लि.

[illegible]

आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाके में भद्राचलम पेपरबोर्ड्स प्लांट में शिफ्ट-ड्यूटी की भीड़-भाड़ शुरु हो गयी। नागेश्वर राव अब घर पहुंचने की जल्दी में है, क्योंकि उनकी बेटी कॉलेज से लौटकर उनकी राह देख रही होगी। मिल के निजी स्कूल में, अपनी दो-दो बहनों के साथ,वह कभी होनहार रत्न थी। आजकल वह कमप्यूटर-विज्ञान की छात्रा है और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसी आइ टी सी कम्पनी का हिस्सा बनना चाहती है, जहां कभी उसके पिता ने काम शुरु किया था।

नागेश्वर आजकल भद्राचलम पेपरबोर्ड्स का गौरवशाली कर्मचारी है। अब वे प्लांट के स्वयं-सम्पूर्ण आवास कॉलोनी में रहते हैं, जिसे 'आधुनिक गांव' का आदर्श रूप दिया गया है और जिसमें हर तरह की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था है। अब पिछली हताशा के सपने की सिर्फ एक खौफनाक याद भर रह गयी है। ऐसा भी एक भयंकर वक्त था, जब उन्होंने अपने बंजर और पैतृक ज़मीन की उम्मीद छोड़ दी थी और इस पिछड़े इलाके से हमेशा के लिए चले जाने का इरादा कर लिया था। लेकिन यह दस साल पहले की बात है—तभी आइ टी सी ने उन्हें राह दिखायी...

भद्राचलम के नागेश्वर राव। उनके लिए पिछड़े इलाके में विकास और तरक्की सिर्फ सपना था।

तभी आइ टी सी ने भद्राचलम पेपरबोर्ड्स की उन्नति और नौकरी के अनगिनत संभावनाओं के ज़रिये उनकी प्रतिभा और समृद्धि को मौका दिया।

प्लांट का अंग्रेजी और तेलुगु माध्यम स्कूल अपने कर्मचारियों के १५०० बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर रहा है।

आइ टी सी द्वारा विकसित भद्राचलम पेपरबोर्ड्स अब १०० करोड़ रुपये के संचालन तक पहुंच गया है। कोर-सेक्टर के पेपर उद्योग को ताज़गी देने के उद्देश्य से इस परियोजना ने पिछड़े इलाके के विकास को प्रेरणा दी है।

आज भद्राचलम व्यापार और उद्योग के गहमागहमी से सरगर्म हो उठा है और जीवन के मूल स्रोत से जुड़ गया है। ग्रामीण-क्षेत्रों के लोगों और आदिवासियों के लिए करीब १२०० प्रत्यक्ष और उससे भी कहीं ज्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है। आज उनकी कमाई भी बढ़ गयी है और जीवन स्तर में भी काफी सुधार आया है। यहां तक कि यह प्लांट लोगों के स्वास्थ्य और इलाज की सुविधायें भी प्रदान करता है।

आज आइ टी सी के अन्यान्य गौरवशाली कार्यों की तरह, भद्राचलम पेपरबोर्ड्स भी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो चुका है। विशिष्ट तकनीक, उत्पादकता और उत्पादन के नये प्रतिमान स्थापित करके, यह परियोजना भी आइ टी सी के लिए महान गर्व का साधन बन चुकी है। कोर-सेक्टर में पिछड़े इलाके के विकास और उसकी अभूतपूर्व सफलता के संकल्प में आइ टी सी अब आदर्श बन चुकी है।

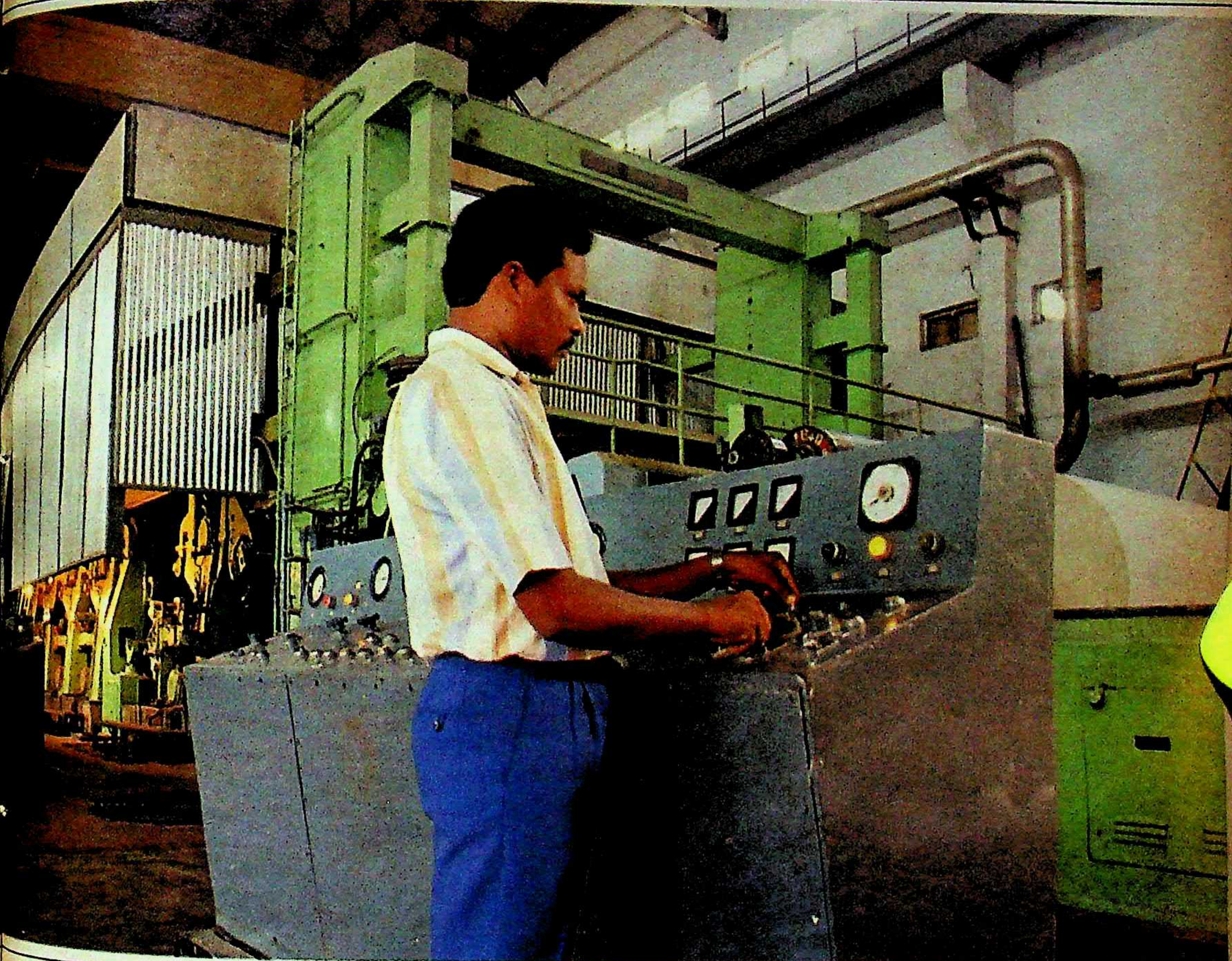

ध्य और
है।
वशाली
भी अपने
तकनीक,
ान स्थापित
के लिए
र-सेक्टर में
अभूतपूर्व
ब आदर्श

ई टी सी भारत के लिए और कहां-कहां कार्यरत है?

उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों त्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और -हज़ार किसानों के फलने-फूलने में मदद दिलेगी। खाद्य-अखाद्य तेलों एवं सहायक उत्पादनों निर्माण और मार्केटिंग के साथ-साथ, आई टी सी ने आयात भी कम किया है।

ीर उद्योग : हथकर्घे, कच्चे माल और तकनीकी विशिष्टताओं के दम पर आई टी सी ने त्रिवेणी लूम्स के ज़रिये शाहजहांपुर की प्राचीन कालीन-बुनाई कला को पुनर्जीवित किया है। अब कालीनों साथ-साथ अन्यान्य लघु और कुटीर उद्योगों की सामग्रियां भी आई टी सी द्वारा निर्यात की जाती हैं।

वार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी करोड़ों की संख्या में -साधन वितरित कर रही है और छोटे परिवार एवं कई साल के अन्तर में सन्तान-प्राप्ति के लाभ चार-प्रसार कर रही है। इसके अथक प्रयासों को सन् १९८८ के एफ आई सी सी आई पुरस्कार म्मानित किया गया है।

I.T.C. Limited

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

Contract. ITC. 91.89 HIN

टिकट की मृगतृष्णा

राजनीति के रेगिस्तान में टिकट की मृगतृष्णा पता नहीं किस-किस को कहां-कहां भटकाती है। जिसके पास जो होता है, वह उसको चुकाकर सत्ता के सपनों के घोड़े पर सवार होने के लिए वहां-वहां दौड़ता है, जहां-जहां उसको उम्मीद होती है कि उसे टिकट मिल सकता है। सत्ता की हवस के सैलाब में डूबते-उतराते व्यक्ति को तिनके का सहारा मिले या ताड़ का, वह किनारे लगने के लिए उससे लटकने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। लेकिन पार लगने से पहले बहुतों को महंगी उतराई देनी पड़ती है और यह भी आवश्यक नहीं कि वे पार लग ही जायें।

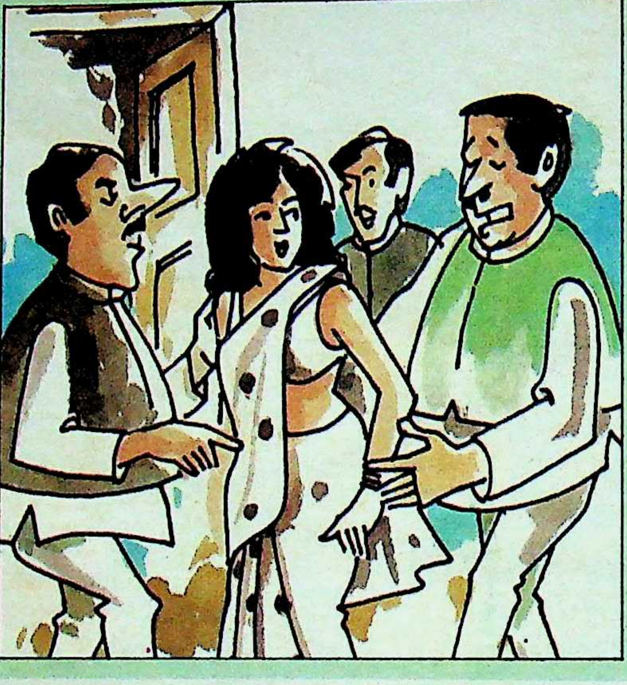

इस समय राजनीति में महिलाओं का 'उद्धार' करने का आह्वान चारों तरफ से हो रहा है। महिलाओं की राजनीति में भारी मांग हो रही है। इस मांग की पूर्ति से पहले कुछ लोग अपनी इच्छा की पूर्ति का काम पहले कर रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसे लोगों के सब्जबाग में फंस भी रही हैं। १८ अक्तूबर को दिल्ली के एक बड़े होटल में एक ऐसी ही सत्ता के सपनों के घोड़े से गिर कर घायल हुई महिला को देखा गया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वह महिला एक टिकट दिलाऊ व्यक्ति के कमरे से निकली थी। अस्त-व्यस्त वस्त्र, छितराये केश और नुचा हुआ चेहरा देखकर सहज ही अंदाज लगाया जा सकता था कि उसे टिकट की क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी। लेकिन इंतहा यह नहीं। इंतहा यह थी कि बजाय थाने जाने के, वह दो-तीन बलवान लोगों के साथ बिना हील-हुज्जत के अस्पताल जा रही थी, क्योंकि उसे न्याय की नहीं चिकित्सा की आवश्यकता थी। आत्मस्वीकृत दुर्गति तक ले जानेवाली हे मृगतृष्णा, तेरा कोई जवाब नहीं! ◆

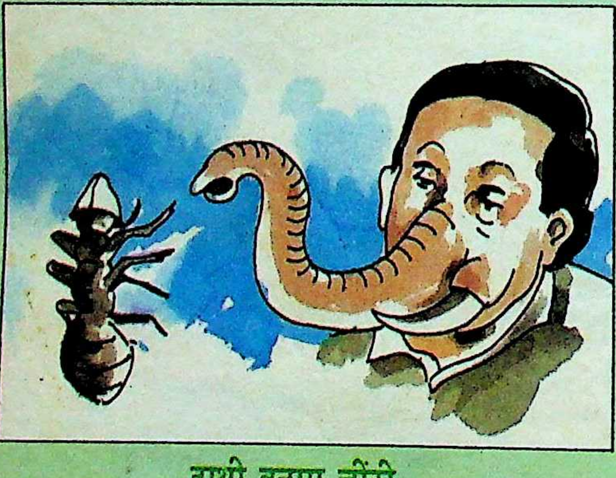

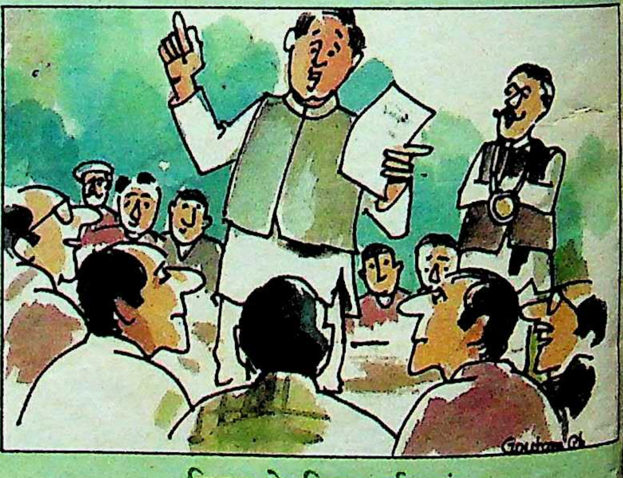

हाथी बनाम चींटी

हास्य से संकट का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। शायद इसीलिए संकट की घड़ी में कांग्रेसियों का हास्य बोध थोड़ा प्रखर हो गया है। अब बिल्हौर (उप्र) के निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी का ही हाल देखिए। खबर है कि बिल्हौर के कांग्रेसी सांसद जगदीश जोशी को जब यह पता चला कि यहां से अरुण नेहरू खड़े किये जा रहे, तो वे भाग कर केंद्रीय मंत्री शीला दीक्षित के पास पहुंचे और कहा, "खुदा के वास्ते मुझे कोई और क्षेत्र दे दीजिए। भला, हाथी और चींटी का भी कोई मुकाबला है?" शीलाजी ने तुरंत ढाढ़साना अंदाज में कहा, "क्या आप नहीं जानते, हाथी यदि किसी से डरता है, तो वह चींटी से ही डरता है।" देखना है यह मिथ असलियत बन पाता है या नहीं! ◆

टिकट के लिए अर्हताएं

दिल्ली में स्थित उत्तर भारत के एक प्रांत के भवन के सामने एक व्यक्ति उत्तेजित होकर जोर-जोर से बोल रहा था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे और उस मजमे की ओर बढ़ रहे थे। एक-दो व्यक्ति उसे शांत करने में लगे थे। वह चीख-चीख कर कह रहा था, "बताइये, मर्डररों, स्मगलरों और रैपिस्टों को टिकट दिया जा रहा है और हम जैसे लोगों को धक्के दिये जा रहे हैं।" उत्तेजित व्यक्ति थोड़ा रुका, तो एक अन्य टिकटार्थी ने उसको सलाह दी, "कोई बात नहीं यार। अब तो तुमको पता चल ही गया कि टिकट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगले चुनाव तक पूरी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है।" इससे पहले कि उत्तेजित व्यक्ति फिर से अपना मुंह खोले, पास खड़ी भीड़ की तालियां और ठहाके गूंज उठे। ◆

रहे हैं। कुछ
सब्जबाग में
अक्तूबर को
ल में एक ऐसी
ड़े से गिर कर
खा गया। एक
वह महिला
क्त के कमरे में
व्यस्त वस्त्र
ा हुआ चेहरा
ज लगाया जा
टकट की क्या
होगी। लेकिन
यह थी कि
वह दो-तीन
बिना हील-
जा रही थी
हीं चिकित्सा
आत्मस्वीकृत
ी हे मृगतृष्णा
!

◆

ो एक अन्य
ाह दी, "कोई
ी तुमको पता
के लिए क्या
हिए। अगले
लो। अभी
ई है।" इसके
क्ति फिर से
खड़ी भीड़ की
ूंज उठे। ◆

Har Safar Main Hum Safar....

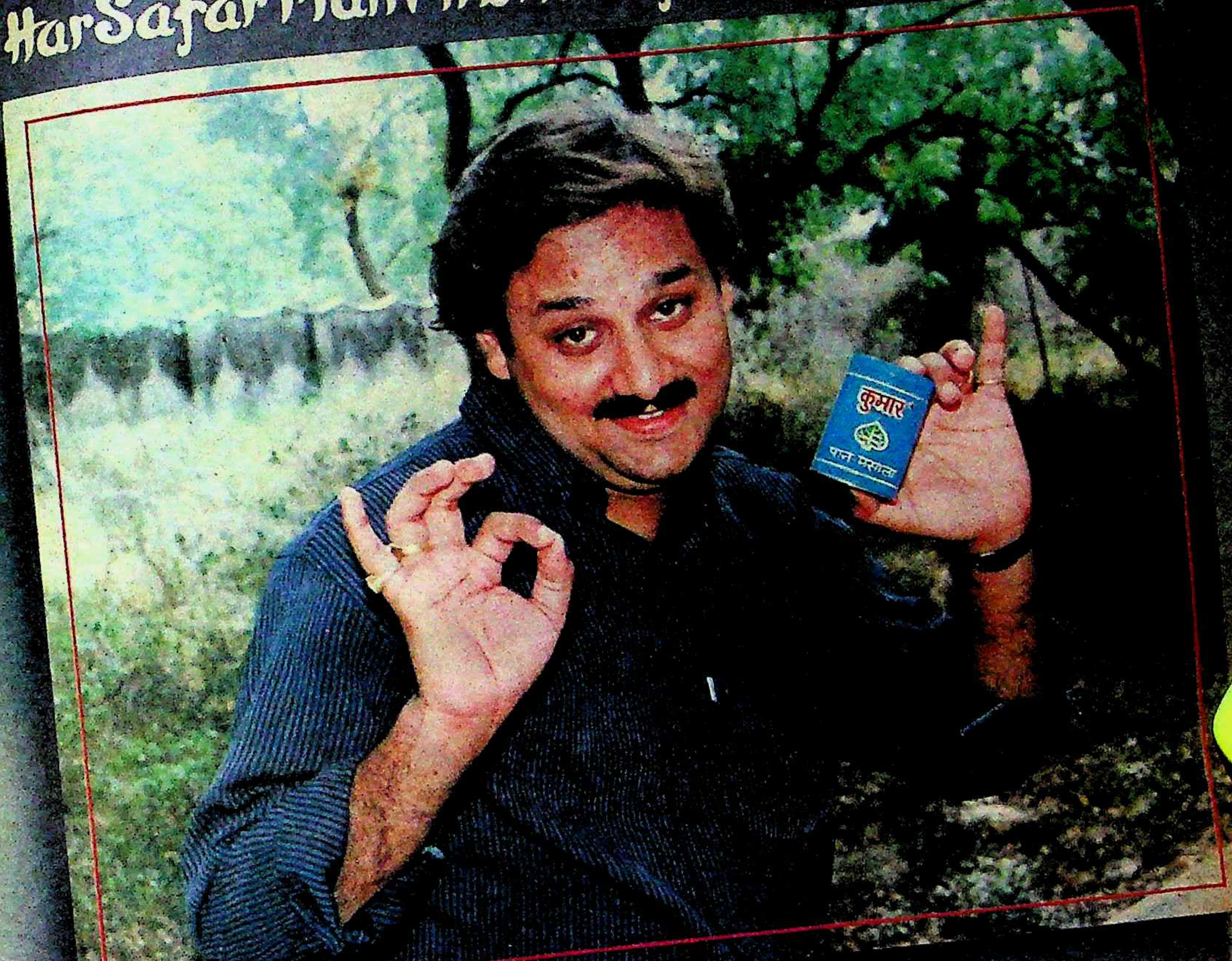

KUMAR®

PAN MASALA

KUMAR®
PAN MASALA
कुमार®
पान मसाला
कुमार®
पान मसाला
ज़र्दा मिक्स

Mfd. by— Kumar Chemicals, Kanpur-208 001
PHONE No. : 52303, 52305

Statutory Warning : Chewing tobacco is injurious to health

NOTE : DEALERSHIP ENQUIRIES SOLICITED FOR UNREPRESENTED AREAS.

CC-0. In Public Domain. Gurukul [illegible] Collection, Haridwar

जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आप दोनों को मिलकर लेना होगा।

कोहिनूर

बेहतरीन गुलाबी कॉन्डोम

आप दोनों ने एक दूसरे का हो जाने व जीवन के उतार-चढ़ाव में साथ निभाने का निर्णय ले लिया है। अब अपने जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का आप दोनों के लिए यही समय है। आप दोनों को सन्तान व अन्य बढ़ती ज़िम्मेदारियों के दैनिक चक्र में बन्धने से पूर्व अपने आप को कुछ वर्ष देने होंगे। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक ऐसे गर्भनिरोधक की जो आप दोनों के अनुकूल हो।

ऐसा गर्भनिरोधक जो सम्पूर्ण सुख व सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर पर अनुचित प्रभाव नहीं डालता, कष्टकर डाक्टरी जाँच को आवश्यक नहीं बनाता व दिन गिनने और तापमान मापने की चिन्ता व तनाव को दूर रखता है। ऐसा सुरक्षित, आसान व विश्वसनीय गर्भनिरोधक है कॉन्डोम।

KOHINOOR
PINK LUXURY CONDOMS

विश्वसनीय कोहिनूर

हज़ारों युवा दम्पत्ति अपने बच्चों के जन्म में उचित अन्तर रख अपने परिवार का नियोजन विश्वसनीय कोहिनूर के सहारे करते हैं। कोहिनूर आपके मिलन के सुख में बाधा डाले बिना बहुत सहज ढंग से आपको सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करता है। यह उच्च कोटि के लेटेक्स रबड़ से बनाया जाता है। सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक जाँच की जाती है। कोहिनूर के निर्माता आपकी एकांतता व सुरक्षा की आवश्यकता को भलिभाँति समझते हैं। कोहिनूर — इसे नाम लेकर ही खरीदिए और विश्वसनीय कोहिनूर के सहारे निश्चिन्त हो जाइए।

कोहिनूर तीन कॉन्डोम व दस कॉन्डोम के पैकेटों में उपलब्ध है।

ttk उत्पादन

परिवार नियोजन — विश्वसनीय कोहिनूर के संग!

MAA COMMUNICATIONS 914A HIN

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र

प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
मुख्य उप संपादक
दिनेश दीनू
उप संपादक
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवींद्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
पटना: विकास कुमार झा
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
दिल्ली: पुनीत टंडन
विशन कुमार
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७१३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५, लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ—२२६००१, फोन: २४८८७८, पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: ३२७२४, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५९ (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९१०३५, जयपुर कार्यालय: ए-२०, शांति पथ, तिलकनगर, जयपुर-४, फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

श्री वीरेंद्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक २४
३१ दिसंबर, १९८९

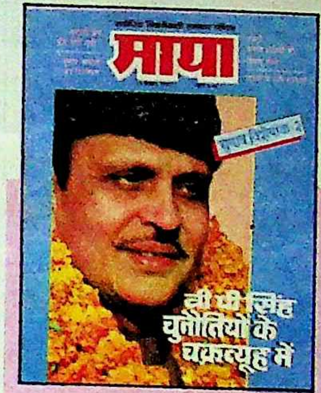

१३

आवरण कथा

वीपी सिंह जिन हालात में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गये हैं, जिस तरह से परस्पर कट्टर विरोधी भाजपा और वामपंथी दलों के सहारे वे प्रधानमंत्री बने हैं तथा मंत्रिमंडल बनाने में उनको जो परेशानी झेलनी पड़ी है, उससे स्पष्ट है कि उन्हें बेहद संकरे और कंटकाकीर्ण मार्ग से गुजरना है। सवाल यही नहीं है कि उन्हें जनता दल के नेताओं की आक्रामक महत्वाकांक्षाओं से जूझना है, बल्कि सवाल यह भी है कि जो अपार जनाकांक्षाएं उन्होंने जगायी हैं, उन्हें पूरा करने की चुनौती भी उनके सामने है। क्या वीपी सिंह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेद पायेंगे?

विशेष रिपोर्ट

हाल के आम चुनाव के परिणामों का विश्लेषण मतदाता की किस सोच की द्योतक है? **८२**

वीपी सिंह

कांग्रेस की नजर में 'देशद्रोही' और 'जिम्मेदारी से भागनेवाले' वीपी सिंह वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं? **२०**

चुनावी जंग

संसद में पहुंचने के लिए विभिन्न दलों और खास नेताओं ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया? **७८**

उत्तर प्रदेश

मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए किस तरह के दांवपेंच खेलने पड़े? **३०**

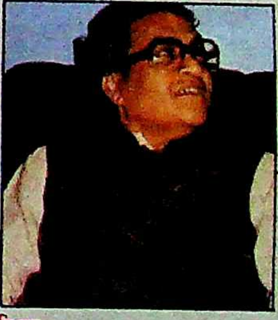

बिहार

जो गद्दी जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के अच्छे दिनों में प्राप्त नहीं कर सके, उसे वे बुरे दिनों में कैसे पा गये? **३८**

राजस्थान

प्रदेश में इंका की अप्रत्याशित हार की वजह राष्ट्रीय मुद्दे रहे या स्थानीय? **६०**

दिल्ली दरबार: सत्ता के चौकीदार १०
आवरण कथा: और वीपी ऐसे बने प्रधानमंत्री १८
चुनाव: अमेठी में बूथ कैप्चरिंग की हिंसक शैली २४
चुनाव: चुनाव परिणामों का गणित २८
चुनाव: उप्र में मतदाताओं ने भाजपा का भ्रम तोड़ा ३३
चुनाव: बिहार में कांग्रेस का पत्ता साफ ४१
चुनाव: मप्र में भाजपा को लाभ ४५
फोटोफीचर ५०
चुनाव: उड़ीसा में [illegible]
चुनाव: नये चेहरे क्या गुल खिलायेंगे? ७०
चुनाव: राष्ट्रीय सरकार की खिचड़ी क्यों नहीं बनी? ७२
घटनाक्रम: बयासी घंटे जिंदगी और मौत के बीच ९०
चुनाव: हरियाणा में अमन के पहले की चुप्पी ९३
चुनाव की झलकियां ९४
कार्टून ९६
असम: गोकुल सैकिया ने आत्महत्या क्यों की? ९८
समाज: चुनाव में हिंसा, हिंसा में चुनाव १००
[illegible] १०२

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ से.मि. एफ.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे का टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली खूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?

ओनिडा २१
पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

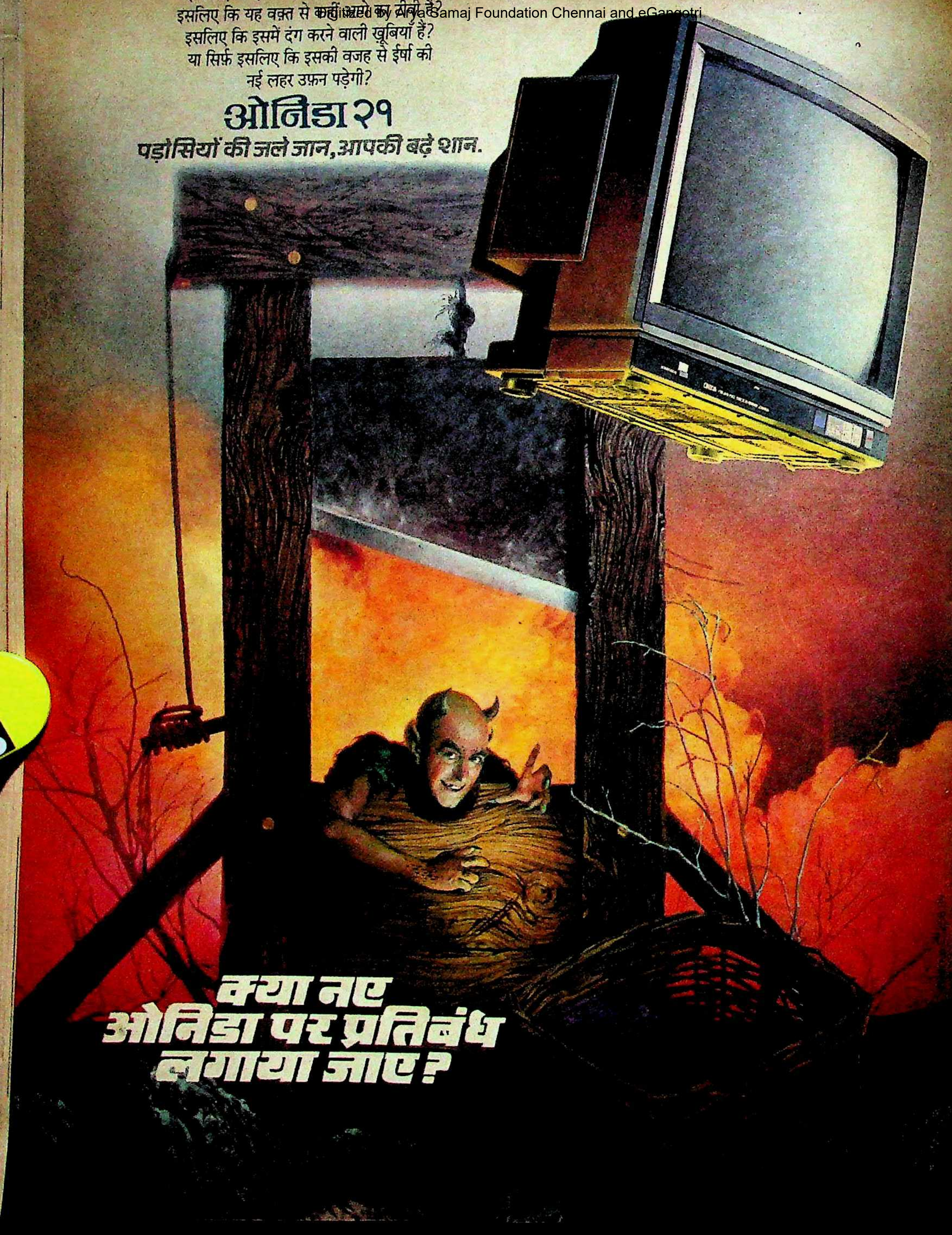
ONIDA
क्या नए
ओनिडा पर प्रतिबंध
लगाया जाए?

संपादक की बात

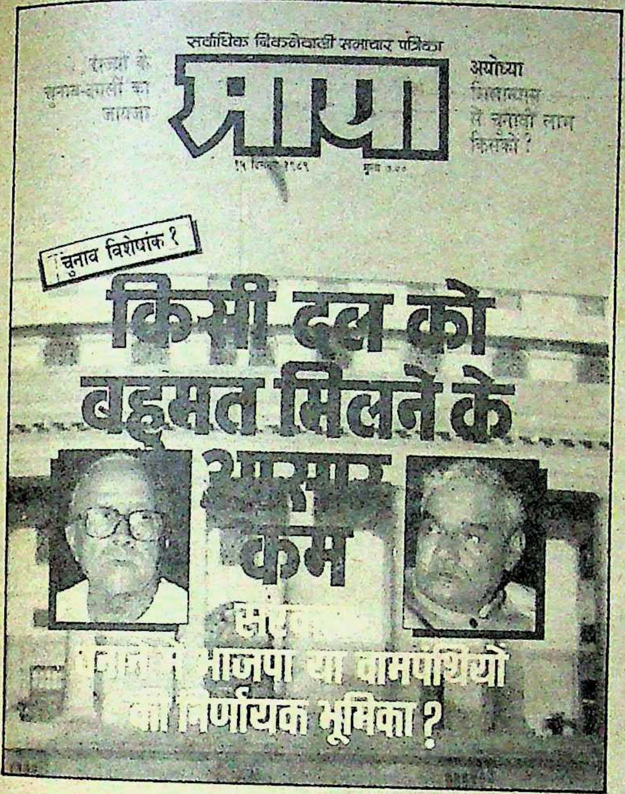
सर्वाधिक बिकनेवाली समाचार पत्रिका

माया

राज्यों के चुनाव-हलचलों का जायजा

अयोध्या शिलान्यास से चुनावी लाभ किसको?

चुनाव विशेषांक १

किसी दल को बहुमत मिलने के आसार कम

[illegible] भाजपा या वामपंथियों की निर्णायक भूमिका?

लोकसभा के चुनाव-नतीजे आने के बाद 'माया' को फोन और पत्रों के जरिये बधाई देने का तांता लगा हुआ है। हमारे सुधी पाठकों को इस बात की खुशी है कि 'माया' ने चुनाव-परिणाम आने के १५ दिन पहले ही जो भविष्यवाणी की थी, वह बिलकुल सही निकली। १६ नवंबर को वितरित हुए १५ दिसंबर, १९८९ के अंक में 'माया' ने कहा था कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और केंद्र में सरकार बनाने की बागडोर भाजपा और वामपंथी दलों के हाथों में होगी। 'माया' के शुभाकांक्षी पाठकों को इस बात का सुखद आश्चर्य भी है कि उसे यह कैसे पता चला कि चुनाव-नतीजे ऐसे होंगे।

दरअसल 'माया ने अनिश्चत चुनाव-परिणामों की सुनिश्चित भविष्यवाणी करने का खतरा किसी ज्योतिषशास्त्र या व्यावसायिक मत-सर्वेक्षकों के बलबूते पर नहीं उठाया था, बल्कि 'माया' की देशव्यापी, अनुभवी, निष्पक्ष और प्रतिबद्ध टीम के आकलन और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर उठाया था। 'माया' की साख और लोकप्रियता का कोई कारण है, तो यही है कि 'माया' देश की भाषा में देश के लोगों से बात करती है, फलतः लोग उससे बेलाग बात करते हैं और 'माया' बिना भाषा के छद्म के लोगों की बात पाठकों तक पहुंचाती है। इसीलिए प्रबुद्ध पाठकों का 'माया' को अमूल्य विश्वास मिला है और वही विश्वास 'माया' की प्रेरणाशक्ति है।

—आलोक मित्र

'माया वह खबर देती है, जिसकी खबर किसी को नहीं'

मैं आपकी 'माया' समाचार पत्रिका का नियमित ग्राहक व पाठक हूं। कभी-कभी तुलनात्मक दृष्टि से 'माया' व अन्य पत्रिकाएं भी साथ-साथ खरीदकर अध्ययन करने का प्रयास कर लेता हूं। यों तो सभी पत्रिकाएं अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं, परंतु 'माया' का कहना ही क्या ! इस पत्रिका को यदि आम हिंदुस्तानी जनता की पत्रिका कहा जाये, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इतने अधिक मूल्य के बावजूद भी 'माया' को नियमित खरीदकर पढ़ने का लोभ नहीं संवरण कर पाता।

पिछले चुनाव विशेषांक में 'किसी दल को बहुमत मिलने के आसार कम'—'सरकार बनाने में भाजपा या वामपंथियों की निर्णायक भूमिका' के प्रस्तुतकर्ता रंजना कक्कड़, त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव व कुमारेश चक्रवर्ती विशेष बधाई के पात्र हैं। केंद्र में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना और आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा व वामपंथियों के बिना सरकार न बन पाने के आसार तो लग रहे थे, परंतु मिली-जुली सरकार के तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करके वाकई 'माया' ने कमाल कर दिखाया।

'माया' सचाई पर से संदेह की परत हटाकर राष्ट्रीय दायित्व निभाती है। राजनीति के दांव-पेंच हों या समाज के कुचक्र सभी के लिए दुधारी तलवार—जिसका वार घातक के लिए संहार और आहत के लिए उपचार है। सही मायने में 'माया' दुराग्रह से मुक्त है, इसीलिए तो 'माया वह खबर देती है, जिसकी किसी को खबर नहीं होती।' **—योगेन्द्र सिंह बघेल, इंदिरा नगर, मानिकपुर, बांदा**

दिसंबर (प्रथम) विशेषांक में चुनाव के भावी परिणामों, संभावनाओं एवं आशंकाओं के संबंध में 'माया' के पत्रकारों द्वारा जो कुछ भी कहा गया, वह पूर्व-कथन अधिकांशतः सच साबित हुआ, और इस प्रकार इस पाक्षिक की पैनी आउटडोर नजरों ने प्रश्न-कुंडली मात्र तक सीमित रहने वाले प्रख्यात ज्योतिषियों की इनडोर दृष्टि को मात दे दिया। अब तो 'माया' को समस्त समाचार पत्रिकाओं की पुरोहित समझा जाना चाहिए। सत्य-असत्य और तथ्य-कथ्य, दोनों के बीच 'दूध का दूध-पानी का पानी' वाला विश्लेषण करने में 'माया' का कोई सानी नहीं। **—सच्चिदानंद तिवारी 'शलभ' चौबीसी, (हैदरगढ़), बाराबंकी**

इस अंक में प्रकाशित तमाम लेख निष्पक्ष व हकीकत से पूर्ण हैं। आकलन के तौर पर 'माया' किसी भी देश की राजनीतिक पत्रिका से हटकर है। और यही कारण है कि इस पत्रिका के पाठक बेताबी से आने वाले हर अंक का इंतजार करते हैं। अंक में प्रकाशित लेख 'किसी भी दल को बहुमत मिलने के आसार कम,' 'राज्यों के चुनाव दंगलों का जायजा', 'चाहे देश जाये भाड़ में,' 'नेकनामी के बजाय बदनामी,' 'चुनाव में दौलत' आदि लेख बहुत पसंद आये। **—चौधरी जगदीश कुलहरि, मु०पो० नवलड़ी, नवलगढ़, झुन्झुनूं, राजस्थान**

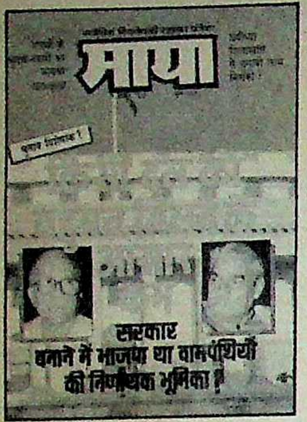

क्या भाजपा या वामपंथियों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती ?

माया' (१५ दिसंबर, १९८९) में आवरण कथा 'क्या भाजपा या वामपंथियों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती ?' बेहद रोमांचक लगी। मैं इस पत्रिका का तहेदिल से सम्मान करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पत्रिका निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरेगी। आपने ठीक ही लिखा है कि पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने-वाला है। खासकर कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सिरमाथे जायेगी।**—संतोष कुमार सिंह, बिहारी धर्मशाला, राजबाड़ी रोड, झरिया, धनबाद**

मेरी हर धड़कन कुरसी के लिए है

माया' का १५ दिसंबर का अंक पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। आज की राजनीतिक स्थिति को नजर में रखते हुए यह कहने में कोई संकोच नहीं कि केसरीजी, फोतेदार, अरुण नंदा, चंद्रशेखर, एनटी रामाराव इत्यादि की हर धड़कन कुरसी के लिए थी। लेकिन जिसके भाग्य में कुरसी थी, उसको कुरसी मिल गयी।**—पप्पू जायसवाल, मिर्जाहयात बेग, दरभंगा**

कांग्रेस को विज्ञापन से नुकसान पहुंचा

इस अंक में आपने कांग्रेस चुनाव के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जा रहे विज्ञापन के संबंध में लिखा है कि कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे विज्ञापन ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सत्य है कि कांग्रेस की पराजय में कांग्रेस द्वारा अपने पक्ष में प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों का काफी योगदान रहा है। इसे कांग्रेस स्वयं नहीं समझ सकी है, नहीं तो ऐसे विज्ञापन वह प्रकाशित ही नहीं कराती।**—सूरज प्रसाद दूबे, जगदीश मंदिर कालोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश**

चुनाव में दौलत

'चुनाव में दौलत' (१५ दिसंबर) पढ़ने को मिला। विज्ञापनों पर अनाप-शनाप खर्च करके, विपक्ष को मुर्गे, बिच्छू के रूप में दिखाकर न जाने सत्तारूढ़ दल क्या साबित करना चाहता था। इन बेसिरपैर के विज्ञापनों को देखकर इनके दिमागी दिवालियेपन का अहसास तो होता ही है। अरबों रुपए विज्ञापन पर न खर्च करके यदि जनता की भलाई हेतु खर्च किये गये होते, तो आज सत्तारूढ़ दल को कुरसी बचाने की शायद इतनी फिक्र न होती।**—दिनेश पुरोहित, सिकंदर पाड़ा स्ट्रीट, कलकत्ता**

शिलान्यास की नाटकीय राजनीति

१५ दिसंबर '८९ की 'माया' में अयोध्या की विशेष रिपोर्ट 'शिलान्यास की नाटकीय राजनीति' पढ़ी। पढ़ते समय हमें ऐसा लग रहा था कि उस विशेष दिन हम अयोध्या में ही यह सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस रिपोर्ट ने मेरी यह हसरत पूर्ण कर दी कि देवोत्थान एकादशी को मैं भी अयोध्या में उस स्थान-विशेष पर रहूं। हालांकि यहां विवाद जैसी कोई बात है ही नहीं, यह तो मात्र कुछ अवसरवादियों और हमें मूर्ख समझनेवाले कुछ तत्वों का स्वार्थपूर्ण शगूफा है। यदि दोनों भाई खुले मस्तिष्क और नरम दृष्टिकोण अपनाकर बिना किसी मध्यस्थ के आमने-सामने बैठकर इस संदर्भ में बातें करें, तो यह कृत्रिम समस्या स्वतः ही सुलझ जायेगी। नहीं तो वही होगा कि 'दो कि लड़ाई में तीसरे को फायदा'। **—श्याम दत्त शर्मा चतुर्वेदी, अरविंद कालोनी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी**

बिहार कांग्रेस-इ : बगावत से जीत खटाई में

१५ दिसंबर, १९८९ की 'माया' मिली जिसमें 'बगावत से जीत खटाई में' पढ़ा। पढ़कर बड़ा ही आनंद आया, क्योंकि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद ही अपने प्रत्याशियों से नाखुश थे। जिन प्रत्याशियों को टिकट न मिलने की उम्मीद थी उन्हें जब टिकट मिल गया, तो मनमुटाव होना ही था। मधुबनी तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही हुआ। इस प्रकार इंका प्रत्याशियों की आपसी कलह के कारण उनकी जीत वास्तव में खटाई में पड़ गयी।**—विवेक कुमार, माण्डू, हजारीबाग**

चीनी इतनी कड़वी कैसे हुई ?

१५ नवंबर, १९८९ की 'माया' में विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत चीनी के कृत्रिम अभाव के बारे में पढ़ा। यह लेख वास्तव में आत्मप्रेरक व साहसी कदम है। चीनी की दलाली में खाये गये रुपए बोफोर्स से भी अधिक हैं। जनता इससे अवश्य जागरूक होगी और रक्षा सौदों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की खरीदारी में दलाली का पर्दाफाश हुआ है।

—जावेद खान, लश्कर, ग्वालियर, मप्र

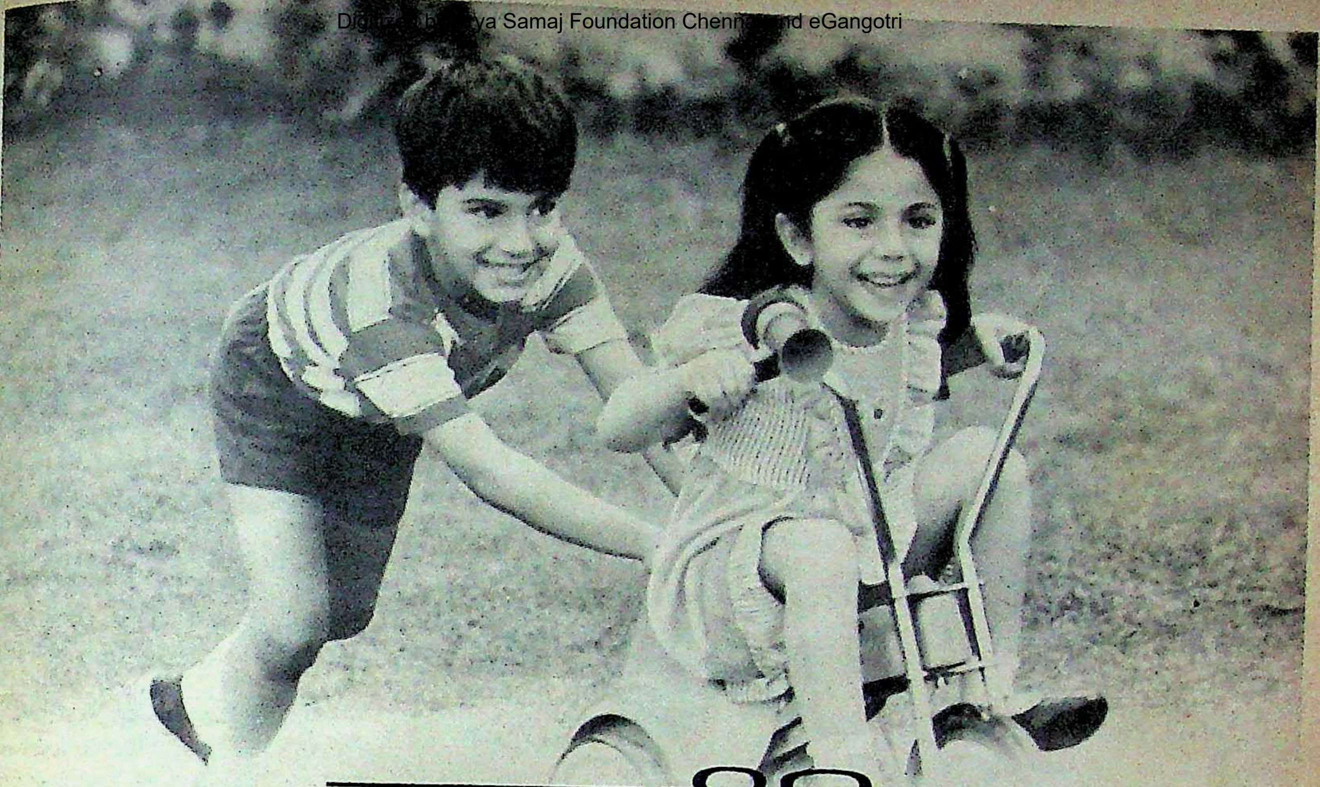

कल्पना कीजिए,
ये दस साल बाद कैसे होंगे!

आपके प्यारे-दुलारे बच्चे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर होंगे, जिन्हें देख आपको गर्व होगा। मां होने के नाते आप उनका जीवन बनाने के लिए सब कुछ जो कर रही हैं।

और आपकी प्यार-भरी देखभाल में उन्हें उचित पौष्टिकता देना भी शामिल है।

हॉर्लिक्स की पौष्टिकता। आपके बढ़ते बच्चों के लिए।

''हॉर्लिक्स में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्त्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज पदार्थ—होते हैं।

और साथ में, मज़बूत दांतों और स्वस्थ हड्डियों के लिए अधिक कैल्शियम भी।

यही है हॉर्लिक्स की पौष्टिकता जिससे आपका बढ़ता बच्चा चुस्त और तन्दुरूस्त रहता है।''

Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nourisher
PROTEINS
VITAMINS
MINERALS
CARBOHYDRATES
CALCIUM ENRICHED
EASY TO DIGEST
ENERGY SOURCE
COMPLETELY NATURAL

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6223 HIN

अरुण नेहरू का स्थान

यों तो काफी जोड़तोड़ के बाद अरुण नेहरू केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गये। लेकिन राजीव गाधी की सरकार में मात्र राज्यमंत्री के रूप में उनका जो दबदबा था, वह इस बार वीपी सिंह सरकार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि अरुण नेहरू का कद कम करने के लिए इस बार शुरू से ही कई प्रभावशाली लोग लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री वीपी सिंह का उनको परोक्ष रूप से समर्थन भी है।

चंद्रशेखर को नेता पद से चुनाव का षड्यंत्र करके हटाये जाने की रणनीति में यों तो कई लोग शामिल थे, लेकिन अब सारा दोष अरुण नेहरू के सिर पर आ रहा है। नयी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री तथा जनता दल के नेता यह मान रहे हैं कि नेता पद के चुनाव में जो अराजनीतिक तरीका चंद्रशेखर को मैदान से हटाने के लिए अपनाया गया, उसमें अरुण नेहरू का सीधा हाथ था।

अरुण नेहरू चंद्रशेखर से काफी नाराज थे। जब चंद्रशेखर को मनाने के लिए तमाम नेता उनके घर पहुंच रहे थे, तो अरुण नेहरू भी गये। अरुण नेहरू ने चंद्रशेखर से कहा कि इस समय देश की जो राजनीति बन रही है, उसमें आपका मैदान से हट जाना ही अच्छा है। इस पर चंद्रशेखर ने नाराज होकर अरुण नेहरू से कहा था, "अरुण, जितनी तुम्हारी उम्र है, उतने सालों से मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे राजनीति समझाने की कोशिश मत करो। अपनी कूटनीति राजीव गांधी और वीपी सिंह को समझाओ।" अरुण नेहरू उसके बाद चुप हो गये और चले आये थे। उसके बाद अरुण नेहरू चंद्रशेखर से मिलने नहीं गये।

अरुण नेहरू दो दिसंबर को जब प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में जा रहे थे, तो सीढ़ियों पर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वीपी सिंह के अलावा कोई और भी शपथ ले रहा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, "नहीं!" लेकिन देवीलाल ने उपप्रधानमंत्री की शपथ ले ली। यद्यपि अरुण नेहरू का तर्क था कि मैंने जानबूझ कर देवीलाल का नाम नहीं बताया। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि वीपी सिंह ने यह जानकारी अरुण नेहरू को नहीं दी थी। इसके बाद जब अशोक हाल में कुर्सियां कम पड़ गयीं, तो अरुण नेहरू ने काफी ऊंचे स्वर में मंत्रिमंडलीय सचिव शेषन से कहा, "कुर्सियों का तुरंत प्रबंध कराया जाये।" इस पर शेषन का जवाब था, "मिस्टर नेहरू, कुर्सियां लगाना मेरा काम नहीं है।" इस पर अरुण नेहरू बिलकुल चुप हो गये।

ऐसा सुनने को मिला है कि वीपी सिंह के घर पर अरुण नेहरू और वीपी सिंह के पुत्र अजेय सिंह में भी किसी बात को लेकर झड़प हो गयी। अरुण नेहरू अजेय सिंह को समझा रहे थे, "अभी तुम बच्चे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। इसलिए तुम चुप रहो।" लेकिन अजेय सिंह ने अरुण नेहरू को जवाब दे दिया, "उतना बच्चा नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं।" इतना ही नहीं, बल्कि वीपी सिंह सरकार के वरिष्ठ मंत्री मधु दंडवते, जार्ज फर्नांडीस, अजीत सिंह आदि भी अरुण नेहरू को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरुण नेहरू अपना महत्व बनाये रखने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। देखना है कि अरुण इसमें कितने सफल होते हैं।

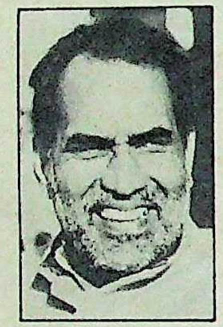

चंद्रशेखर के पांच सूत्र

जनता पार्टी के संस्थापक—अध्यक्ष चंद्रशेखर इस समय अपना अधिक से अधिक समय दिल्ली से ४० किलोमीटर दूर गुड़गांव (हरियाणा) के अपने भारत यात्रा केंद्र भोंडसी में बिता रहें हैं। कभी-कभी कुछ देर के लिए वे अपने ३, साउथ एवेन्यू स्थित आवास पर आते हैं या फिर आईटीओ स्थित आचार्य नरेंद्र देव निकेतन के कार्यालय में बैठते हैं। ज्यादातर जो उनसे मिलना चाहता है, वह भोंडसी पहुंच जाता है।

प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने चंद्रशेखर से इधर मेल-मिलाप की जितनी भी कोशिशें कीं, वे सब बेकार गयीं। वैसे कुछ लोग अभी भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वीपी सिंह से उनका कोई समझौता हो जाये। इधर मंत्रिमंडल में जिन लोगों को स्थान नहीं मिला है, वे लोग अकसर चंद्रशेखर के यहां देखे जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर उनको कोई खास घास नहीं डाल रहे हैं। उनका कहना है, "मैं ऐसे लोगों का कोई सहयोग नहीं लेना चाहता हूं जो अपने निहित स्वार्थों की वजह से वीपी सिंह का विरोध कर रहे हैं।" इसमें जनता दल के महामंत्री यशवंत सिन्हा प्रमुख हैं जो कैबिनेट मंत्री न बनाये जाने के कारण वीपी सिंह से काफी अप्रसन्न हैं।

जब लखनऊ में अजीत सिंह मुख्यमंत्री का चुनाव मुलायम सिंह यादव से हार गये थे, तो वे दिल्ली पहुंचते ही सीधे चंद्रशेखर के भोंडसी स्थित आश्रम पहुंचे। चंद्रशेखर ने उनको सलाह दी कि वे वीपी सिंह सरकार में शामिल हो जायें क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा है। अजीत सिंह को चंद्रशेखर की यह बात बहुत अच्छी नहीं लगी, जब उन्होंने कहा, "आपकी राजनीति अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करने की है। इसलिए आपको वीपी सिंह का विरोध नहीं करना चाहिए।"

चंद्रशेखर ने काफी मनन के बाद अपने पांच सूत्री सिद्धांत बनाये हैं। पहला, जब कभी कोई मौका चुनाव का आयेगा, तो वे वीपी सिंह के खिलाफ लड़ने से कभी नहीं हटेंगे। दूसरा, वीपी सिंह की सरकार में कभी भी किसी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। तीसरा, पार्टी का कोई पद नहीं लेंगे। चौथा, संसद में वीपी सिंह की सरकार के विरुद्ध कभी नहीं जायेंगे। हमेशा उसके समर्थन में वोट देंगे। संसद में वीपी सिंह की कभी आलोचना नहीं करेंगे। पांचवा, अगर वीपी सिंह के ऊपर कोई हमला होगा, तो उनको बचाने के लिए खड़े नही होंगे।

कुल मिलाकर चंद्रशेखर के पास आज इतने सांसद नहीं हैं कि वे वीपी सिंह को कोई चुनौती दे सकें, लेकिन उनके पास एक नैतिक आधार इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह उनसे घबराये हुए हैं। वीपी सिंह के समर्थक खासकर अरुण नेहरू ने जिस तरह उनको अंधेरे में रखकर नेता पद का चुनाव कराया था, उससे यह नैतिक आधार चंद्रशेखर को मिला।

आडवाणी साहब गलत जगह पहुंचे

न कोई इस तरह मिलने के लिए जाने की कल्पना कर सकता था और न इस तरह पलक-पांवड़े बिछाने की प्रत्याशा कर सकता था, लेकिन हुआ यही। दरअसल भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी कार में बैठते ही अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री आवास चलो। ड्राइवर ने आव देखा न ताव पहुंच गया ७ रेसकोर्स पर। अंदर खबर हुई कि आडवाणी साहब मिलने आये हैं। अंदर वाले ने अंदर खबर दी, तो तुरंत जवाब मिला गाड़ी सहित अंदर आने दें। आडवाणी साहब की आंखें तब खुलीं, जब वे पूर्व प्रधानमंत्री के सचिव के कमरे में पहुंचे। वहां वही वी जार्ज बैठे थे। आडवाणी साहब ड्राइवर को कोसने के सिवा क्या कर सकते थे? ■

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

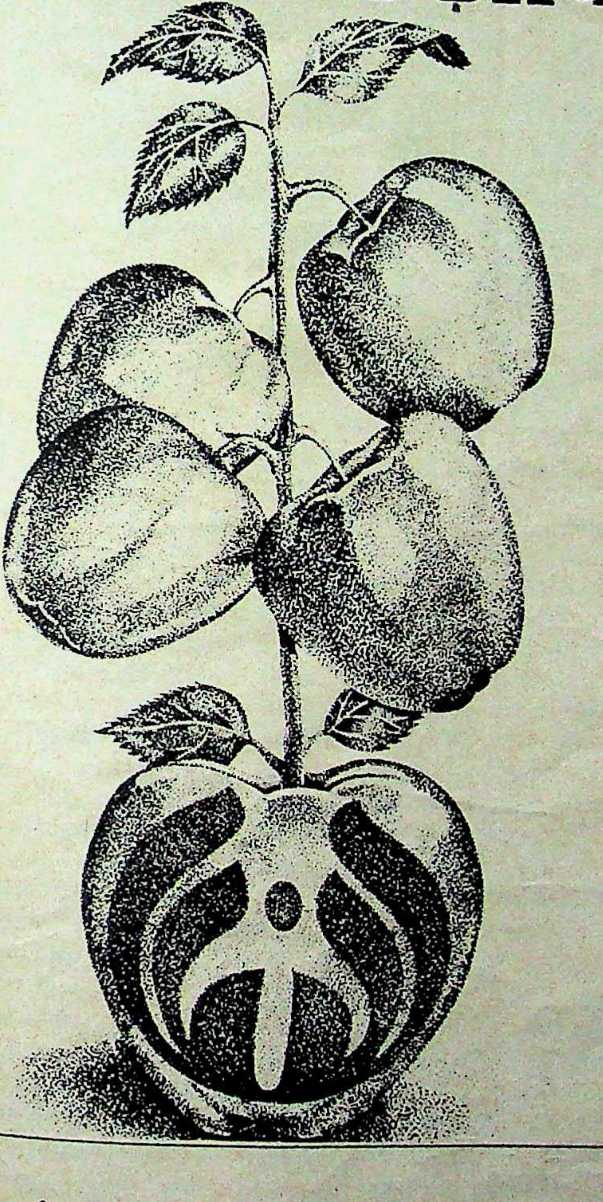

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टावर, कफ़ परेड, कोलाबा, बम्बई 400 005.

Sobhagya-B/89 HN

सत्ता के चौकीदार

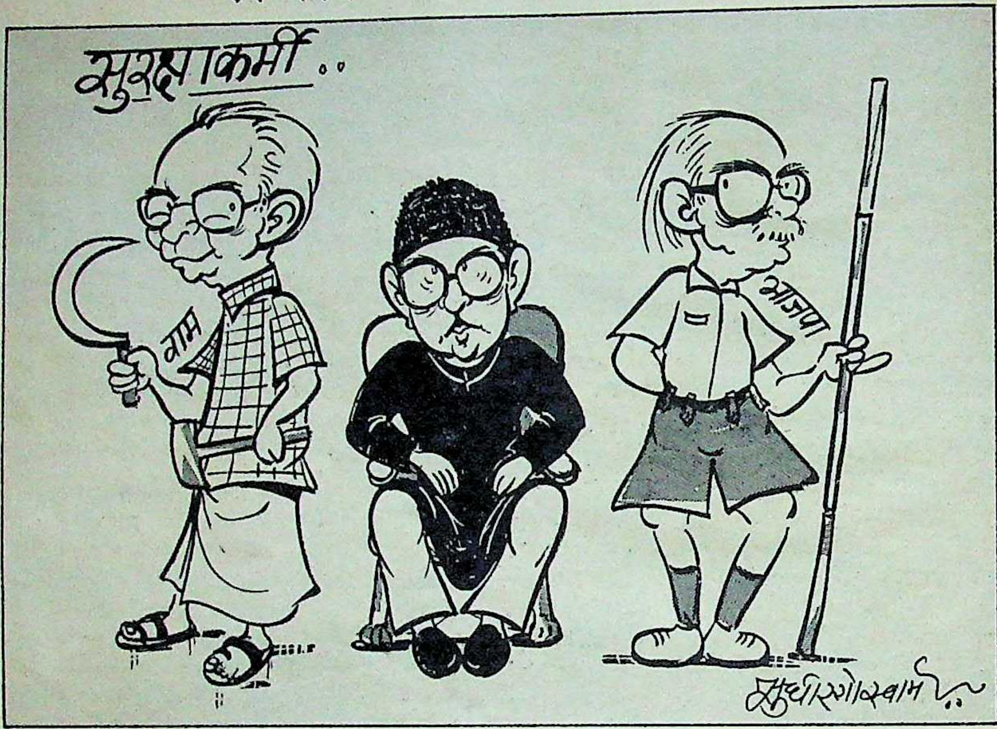

२६ नवंबर की शाम से रात तक ज्यों-ज्यों लोकसभा के चुनावी नतीजे दिल्ली दरबार में घुसने लगे, त्यों-त्यों एक-एक करके वहां चमचमाते दूधिया बल्ब 'फ्यूज' होने लगे। अर्धरात्रि तक दिल्ली दरबार (राजीव गांधी) की बत्ती गुल हो गयी। गहन अंधेरे और खौफनाक सन्नाटे में केवल एक दिया (नेता विरोधी दल) टिमटिमा रहा था। निवर्तमान दिल्ली दरबार सिंहासन बत्तीसी पर घड़ों आंसू बहा रहे थे और बार-बार यही शेर दोहरा रहे थे, "खंडहर में कुछ दिये हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बहुत उदास है रात!" दूरदर्शन पर सारी रात प्रणय राय चिल्लाते रहे—"सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।"

निवर्तमान दिल्ली दरबार के अंत्री-मंत्री-संत्री २७ नवंबर की सुबह से अपना बोरिया-बिस्तर गोल करने में जुट गये। ताऊ (चौ० देवीलाल) वाया चंडीगढ़ रात में दिल्ली के अपने हरियाणा भवन में आकर बैठ गये। जब वे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होने लगे, तो खबरचियों ने पूछा, "ताऊ तूने कहा था कि २७ नवंबर को हरियाणा विधानसभा भंग करके चुनाव करायेगा?" ताऊ ने अपनी हरियाणवी में खबरचियों पर लट्ठ तान दिया, "नहीं करता विधानसभा भंग, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है?" हरियाणा भवन में पहुंचते ही ताऊ ने राजा मांडा को फोन कराया, "आ जा भाई। जनता से चुनाव में जो लूटकर लाये हैं, उसका बंटवारा कर लें।" राजा मांडा (वीपी सिंह) भड़क गये, "ताऊ, मैं राजा हूं। सिपाही राजा के लिए लड़ते हैं। लड़ाई में सिपाही जो भी जीतते हैं, उस पर राजा का अधिकार होता है। चाहो तो बीआर चोपड़ा का महाभारत देख लो।" ताऊ ने अपने बेटे (ओमप्रकाश चौटाला) का तकिया लगाते हुए कहा, "देख राजा, मेरे सिरहाने बलिया का ठाकुर (चंद्रशेखर) खड़ा है। बंटवारे के बारे में तू अच्छी तरह सोच ले। अगर समझ में आ जाये, तो मेरे पैंताने आ खड़ा हो जा। फिलहाल मैं लूट कर माल अपने सीने पर रखकर खर्राटे भरने के मूड में हूं।" राजा मांडा तुनक गये। बाहर एक गोरी चमड़ी का विदेशी खबरची राजा मांडा का इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा था। राजा ने उसे अंदर बुला लिया। उस खबरची का पहला सवाल था, "मिस्टर सिंह, आप बोला था कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब आपका क्या बोलना है?" राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यस मिस्टर गोरी चमड़ी! मैंने जो कल बोला था, वही आज बोल रहा हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूं।" गोरी चमड़ी के खबरची के जाते ही अरुण नेहरू अपनी भारी भरकम काया के साथ राजा मांडा पर चढ़ बैठे, "राजा! नाटक बंद करो। यह मौका इस तरह के इंटरव्यू देने का नहीं है। यह समय ऐसी रणनीति बनाने का है, जिसमें बलिया का ठाकुर और हरियाणा का ताऊ आपस में टकरा जायें। तुमको इस समय अज्ञातवास में जाना होगा।" अज्ञातवास का नाम सुनकर राजा थोड़ा घबराये। लेकिन मरता क्या न करता? राजा ने अपनी मुड़िया हिला दी।

राजा मांडा की तरफ से अरुण नेहरू का फोन ज्योति बसु को कलकत्ता पहुंच गया था, "राजा मांडा को बलिया के ठाकुर ने हरियाणा के ताऊ के साथ मिलकर दबोच लिया है। चंद्रास्वामी ने अपना तंत्र-मंत्र दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चालू कर दिया है।" ज्योति बाबू ने कहा, "घबराओ नहीं। मैं आज रात ही आकाशीय मार्ग से दिल्ली में आ टपकता हूं।" इधर साईं (लालकृष्ण आडवानी) भड़के हुए थे। अटलबिहारी वाजपेयी उनको समझा रहे थे, "साईं, राष्ट्रीय सरकार का आइडिया ही अच्छा रहेगा। हम भी सरकार में, तुम भी सरकार में। अपना केसरिया झंडा ज्योति बसु के लाल झंडे से सीधा थोड़े ही मिलेगा। बीच में राजा का हरा झंडा भी तो रहेगा।"

आडवाणी ने अपनी बत्तीसी पीसते हुए कहा, "अरे अटल साईं, तू समझ क्यों नहीं रहा है? नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) हम लोगों को कच्चा चबा लेगा।" अटलजी नागपुर का नाम सुनते ही ढीले पड़ गये। आडवाणी ने बात पलटी, "अरे अटल साईं, उस वीपी के बच्चे को नाक रगड़वाये बिना समर्थन नहीं देंगे। उसका 'नेचुरल एलाई' का सारा 'फितूर' निकाल देना होगा।"

ज्योति बसु रात को दिल्ली के बंग भवन में आ ही धमके। वहां थोड़ी देर के बाद ही 'राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है' की मद्धिम ध्वनि के साथ राजा मांडा बदहवासी के आलम में पहुंच गये। उनके साथ अपने 'पाकेट कंप्यूटर' पर जोड़तोड़ करते हुए अरुण नेहरू भी थे। राजा मांडा के मुंह से कुछ फूटे कि उसके पहले अरुण नेहरू ने बात शुरू कर दी, "बसु दा, लेफ्ट सपोर्ट के साथ अगर आप यह शर्त लगा दें कि वीपी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ही हमारा समर्थन है।" ज्योति ने बात काट दी, "प्राइवेटली यह कह सकता हूं। पब्लिकली यह कहने में मुश्किल होगी। ईएमएस और सुरजीत पोलितब्यूरो में मुझे उखाड़ फेंकेंगे।" ज्योति बसु की बात सुनकर राजा मांडा ने बगुले की तरह अपनी गरदन कंधे पर जब डाल दी, तो ज्योति बसु ने उनकी गरदन अपने हाथों से सीधी करते हुए कहा, "कामरेड राजा मांडा, इतना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सीमाएं हैं। लेकिन हम अपनी सीमाओं में पूरी कोशिश करेंगे।"

दिल्ली के ३ साउथ एवेन्यू लेन स्थित बलिया के ठाकुर की कुटिया में भीड़ जुटी हुई थी। बलिया के ठाकुर अपनी कुटिया में लेटे बुरी तरह कांप रहे थे। उनको जूड़ी चढ़ी हुई थी। दर्जनों कंबल उनके ऊपर डाले जा चुके थे, लेकिन उनकी कंपकंपी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। मुलायम सिंह अपनी मुलायम-मुलायम बात करके लौट चुके थे। चंद्रशेखरजी की जूड़ी में मुलायम सिंह की बातों ने कोई गरमाई नहीं पहुंचाई। मुलायम हर बात के आगे-पीछे कहे जा रहे थे, "मेरी यूपी की मुख्यमंत्री की लाटरी निकलवा दो, दिल्ली में बाकी सब ठीक हो जायेगा। अजीत सिंह मेरी छाती पर बुरी तरह सवार है।" मुलायम सिंह के जाते ही ओम प्रकाश चौटाला कुटिया में पहुंच गये थे, "अध्यक्षजी, (चंद्रशेखरजी को अध्यक्षजी कहकर ही संबोधित किया जाता है) बाप मरेगा तब ही खेत बिकेंगे। बाप कभी मुझे तकिया बनाकर हरियाणा भवन में आराम करता है, तो कभी रणजीत (छोटे भाई) को अपने सिरहाने लगा लेता है। उसे आप हरियाणा से हटाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनवा दो, तो मेरे सारे पाप कट जायें। अब मेरी भी उम्र हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की हो गयी है।" चंद्रशेखर ने कंबल ओढ़-ओढ़े कहा, "अगर चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बनें, तो मुझे कोई खास एतराज नहीं है। लेकिन विश्वनाथ को मैं नहीं बनने दूंगा।" इसी बीच जैल सिंह का फोन आ गया, "काका, तू मेरे पास आ जा। मेरे पास जूड़ी उतारने का खास पटियाली नुस्खा है। ज्योति बसु मेरे पास बैठा हुआ है।" चंद्रशेखर तुरंत उठ बैठे और कंबलों से निकलकर ज्ञानी जैल सिंह के सरकुलर रोड स्थित बंगले की तरफ 'ज्ञान' लेने के लिए लपक लिये।

एक दिसंबर को उड़ीसा भवन में दोपहर को बीजू के सौजन्य से अरुण नेहरू ने खिचड़ी पकायी। खिचड़ी के पकते ही अरुण नेहरू ने उसे थाली में परोस कर ताऊ के सामने रखा, "चौधरी साहब, खायें। बहुत लजीज बनी है। जल्दी से खाकर चलें, संसद के सेंट्रल हाल में नये नेता का तीन बजे चुनाव करना है।" वीपी सिंह थाली को ललचाई नजरों से देख रहे थे। पास बैठे अजीत सिंह के मुंह में भी पानी आ रहा था। ताऊ ने थाली को अपने आगे से खिसका दिया, "बलिया का ठाकुर कहां है? उसकी इजाजत के बिना अगर मैंने यह खिचड़ी खा ली, तो मुझे पचेगी नहीं।" बीजू पटनायक को ताऊ ने इशारा किया कि चंद्रशेखर को लेकर आओ। बीजू बलिया के ठाकुर की कुटिया में पहुंचे, तो वहां रघुनाथ झा उनको समझा रहे थे, "अध्यक्षजी, हम फिर आपको कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग राजा मांडा के नाम पर जीत सकते हैं। वैसे हम तो आपके साथ...।" त्योरी चढ़ाकर चंद्रशेखरजी ने रघुनाथ झा को दबोच लिया। प्रबोध कांत कुछ बोलें कि उसके पहले ही बीजू आ पहुंचे, "चंद्रशेखरजी, प्रधानमंत्री की खिचड़ी तैयार हो चुकी है। देवीलाल उसे खाने के लिए तैयार हो गये। लेकिन उनकी शर्त यह है कि जब तक चंद्रशेखरजी नहीं कहेंगे, वे थाली में हाथ नहीं लगायेंगे।" चंद्रशेखरजी ने अपनी खिचड़ी दाढ़ी खुजलायी, "ठीक है, विश्वनाथ को खिचड़ी खाने को नहीं मिल रही है, तो मुझे देवीलाल के खाने पर कोई आपत्ति नहीं है।"

जब राजा मांडा रात को हरियाणा भवन पहुंचे, तो ताऊ ने 'उप प्रधानमंत्री' बनने के लिए थाली की आधी खिचड़ी खुद खा ली। इसी समय यह भी तय कर लिया, "मुलायम सिंह को यूपी की सूबेदारी देनी होगी। जनमोर्चा के विधायक लखनऊ में अजीत सिंह को समर्थन नहीं देंगे।"

संसद के सेंट्रल हाल में नवनिर्वाचित जनता दल के सांसद एकत्र थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होनेवाला है। देवीलाल और चंद्रशेखर एक कार में आये। एक दूसरी कार में वीपी सिंह अजीत सिंह के साथ आये। मधु दंडवते ने सभा की कार्यवाही शुरू की। राजा मांडा ने खड़े होकर चौ० देवीलाल की तरफ प्रधानमंत्री रूपी खिचड़ी की थाली बढ़ाते हुए कहा, "ताऊ आपने बहुत मेहनत की है, इस थाली पर आपका ही हक बनता है।" चंद्रशेखरजी ने तुरंत खड़े होकर समर्थन किया। पूरे सेंट्रल हाल में सन्नाटा छा गया। देवीलाल ने अपने हाथ में थाली ली और खाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन दूसरे ही क्षण उनका हाथ रुक गया। वे बोल पड़े, "अब यह थाली मेरी है। मैं अभी तक केवल हरियाणा का ताऊ था। लेकिन मेरी इच्छा 'जगत ताऊ' बनने की है। इसलिए मैं यह थाली विश्वनाथ-प्रताप सिंह को खाने के लिए दे रहा हूं।" अजीत सिंह फुरती से उठे और उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। मधु दंडवते ने एक सेकिंड की भी देरी नहीं की और माइक पर चिल्ला दिये, "विश्वनाथप्रताप सिंह नेता चुन लिये गये।" चंद्रशेखरजी कुछ भी समझ नहीं पाये कि आखिर यह क्या हुआ? चिमनभाई पटेल ने इशारे में अरुण नेहरू से पूछा, "क्या चंद्रशेखरजी को नाटक का दूसरा दृश्य नहीं बताया गया था?" अरुण नेहरू ने इशारे में गरदन हिलाकर बताया कि "नहीं!" इसी बीच चंद्रशेखरजी चीख पड़े, "धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है।"

संसद भवन के बाहर नारे लग रहे थे, "राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है।" इसी नारे के शोर के बीच चौ० देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से कान में कहा, "रात में हरियाणा भवन आओ। पूरी खिचड़ी तुम अकेले नहीं खा सकते हो।" जब राजा मांडा रात को हरियाणा भवन पहुंचे, तो ताऊ ने 'उप प्रधानमंत्री' बनने के लिए थाली की आधी खिचड़ी खुद खा ली। इसी समय यह भी तय कर लिया, "मुलायम सिंह को यूपी की सूबेदारी देनी होगी। जनमोर्चा के विधायक लखनऊ में अजीत सिंह को समर्थन नहीं देंगे।"

इस प्रकार दिल्ली दरबार में वीपी सिंह का प्रवेश हुआ, "राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है।"

—दरबारी लाल

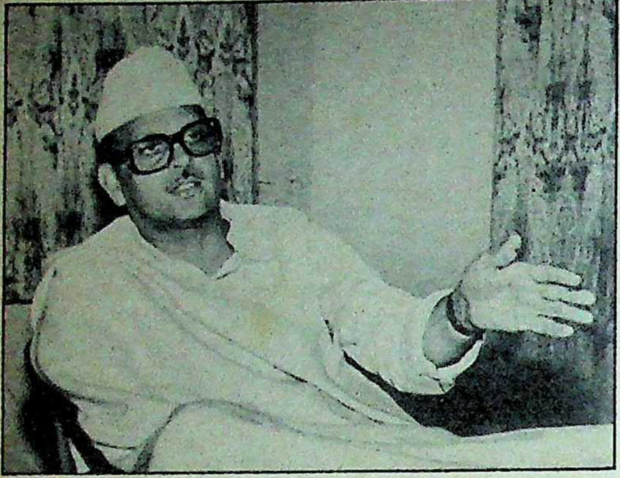

वीपी सिंह

अमेठी का गोलीकांड दो बातों का खुला सबूत है: एक, इसका कि कांग्रेस-इ ने चुनाव-प्रक्रिया और लोकतांत्रिक सस्थाओं को किस हद तक नष्ट कर रखा है और दूसरा, इसका कि वह बैलट पर नहीं, बल्कि बुलेट पर ही विश्वास करती है। **—राजमोहन गांधी, हिंदुस्तान टाइम्स**

यह हमला मेरे पति पर नहीं, लोकतंत्र पर हुआ है जिसे लोकशक्ति कभी क्षमा नहीं करेगी। **—श्रीमती गरिमा सिंह (डा० संजय सिंह की पत्नी)**

मैं पिछले पांच वर्षों तक चिताग्रस्त रहा हूं, अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के चिताग्रस्त रहने की बारी है। **—राजीव गांधी**

सालभर के अंदर ही फिर चुनाव होना तय है। इस दौरान जद जीत की खुशी में और कांग्रेस हार के गम में डूबी रहेगी और हम (बसपा) अपना आधार मजबूत कर लेंगे। **—कांशीराम**

अमेठी में फिर से आम चुनाव की विपक्षी मांग, राजीव गांधी को लोकसभा से बाहर रखने की चाल है। **—आनंद शर्मा, इंका प्रवक्ता**

प्रधानमंत्री पद के निर्णय में मुझे अंधकार में रखा गया है और चटपट अपनी वाली कर ली गयी।

—चंद्रशेखर

हमने इस भ्रष्ट कांग्रेस-इ शासन को उखाड़ फेंकने और देशवासियों को बांटनेवाली उसकी सरेआम सांप्रदायिक साजिश को नाकाम करने का निश्चय कर लिया है। **—वीपी, चंद्रशेखर, देवीलाल, अजीत सिंह और हेगड़े, संयुक्त वक्तव्य**

न दक्षिण की न वाम की,
अबकी लहर है राम की।
—भाजपा का नारा (देवरिया में)

चूजा (अनिल शास्त्री) तो ऐसा चीता निकला कि गजराज मोशाय (केंद्रीय मंत्री श्यामलाल यादव) बिना मुकाबला किये ही चारों खाने चित्त हो गये, वह भी अपने ही वन में। **—बंगला लेखक शांतिरंजन गांगुली (वाराणसी)**

जिन कांग्रेसजनों ने इस (अयोध्या) यात्रा में मेरा साथ नहीं दिया, वे राष्ट्रभक्त नहीं, बल्कि केवल सत्ताकांक्षी हैं। **—कमलापति त्रिपाठी**

कमलापति (त्रिपाठी) अब काशी छोड़ें और बाबरी मस्जिद में ही रहें, ताकि रोज तीनों वक्त की नमाज अदा कर सकें। **—कवि चंद्रशेखर मिश्र, गांडीव**

(आम चुनाव में) जहां-जहां इंका को हार दिखी, वहीं-वहीं हिंसा भड़की, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और अपराधी दस्तों की बदतमीजियां हुईं—क्यों, आखिर क्यों? **—अनिल शास्त्री, स्वतंत्र भारत**

कांग्रेस के पास अब कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा है और यदि वह यह (हिंदू) पत्ता खेले भी, तो इसका लाभ दूसरों को मिलेगा। **—चंद्रशेखर**

हमारे लिए भाजपा पहले नंबर की दोस्त है और कांग्रेस-इ दूसरे नंबर की। **—महंत अवैद्यनाथ, रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष**

मैं वामपंथियों से अच्छा वामपंथी हूं—मेरे विचार और कार्यकलाप बता देंगे कि मैं वामपंथी हूं। **—प्रियरंजन दासमुंशी**

एक बार दिल्ली की हुकूमत मेरे हाथ में आ जाये, तो मैं सबकुछ गांवों (के विकास) में लगा दूंगा। **—देवीलाल**

जब दिल्ली कमजोर होती है, तब राष्ट्र कमजोर हो जाता है। **—राजीव गांधी**

राजीव गांधी

मैं बाल ठाकरे का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन उनकी इस बात से सहमत हूं कि राजीव गांधी को इटली में क्रिसमस (बड़ा दिन) मनाना चाहिए। **—मीनू मसानी**

वीपी सिंह जब फूलन देवी को सही रास्ते पर नहीं ला सकते, तो बेनजीर भुट्टो से कैसे निपट सकते हैं? **—अकबर अहमद डंपी**

भाजपा ने मुझे नहीं, मैंने भाजपा को अपनाया है। **—सिकंदर बख्त**

आज वे सब (कांग्रेसी मुसलमान) सिकंदर बख्त बन गये हैं। **—हरकिशन सिंह सुरजीत**

इस तरह की कांग्रेसविरोधी हवा मैंने पहले कभी नहीं देखी। **—रामकृष्ण हेगड़े**

वह (जयललिता) आजकल की झांसी की रानी हैं। **—राजीव गांधी**

पुलिस कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के मुताबिक काम करती है। **—किरण बेदी**

मैं राजनीति छोड़ चुका हूं। फिर उसमें क्यों आऊं? दुबारा गिरने के लिए? जो हुआ सो हुआ, बस शुक्रिया। **—अमिताभ बच्चन**

मैं प्रधानमंत्री परिवार की ही एक सदस्य हूं, मैंने उस परिवार में कभी किसी को खुश नहीं देखा। **—मेनका गांधी**

चाहे कुछ भी हो, मैं राष्ट्र की अखंडता के लिए और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ता रहूंगा। **—राजीव गांधी**

कांग्रेस-इ ने अवाम का प्यार खो दिया है। **—अहमद बुखारी, शाही इमाम के प्रवक्ता**

प्रधानमंत्री ने वोट के लिए अपने परिवार के छोटे-बड़े हर सदस्य को दरवाजे-दरवाजे घुमा दिया, क्या यह अपने आप में हार का इजहार नहीं है? **—वीपी सिंह**

अगर हम हरियाणा में देवीलाल और दिल्ली में वीपी सिंह को सत्तासीन करा दें, तो एक हफ्ते में पंजाब समस्या को हल कर लेंगे। **—खुशवंत सिंह**

अपने यहां के कुछेक अखबारों को पढ़िए, तो लगेगा मानो यह देश एक पेट्रोल की झील है जो एक जलती तिल्ली का इंतजार कर रही हो। **—गोर्बाचेव**

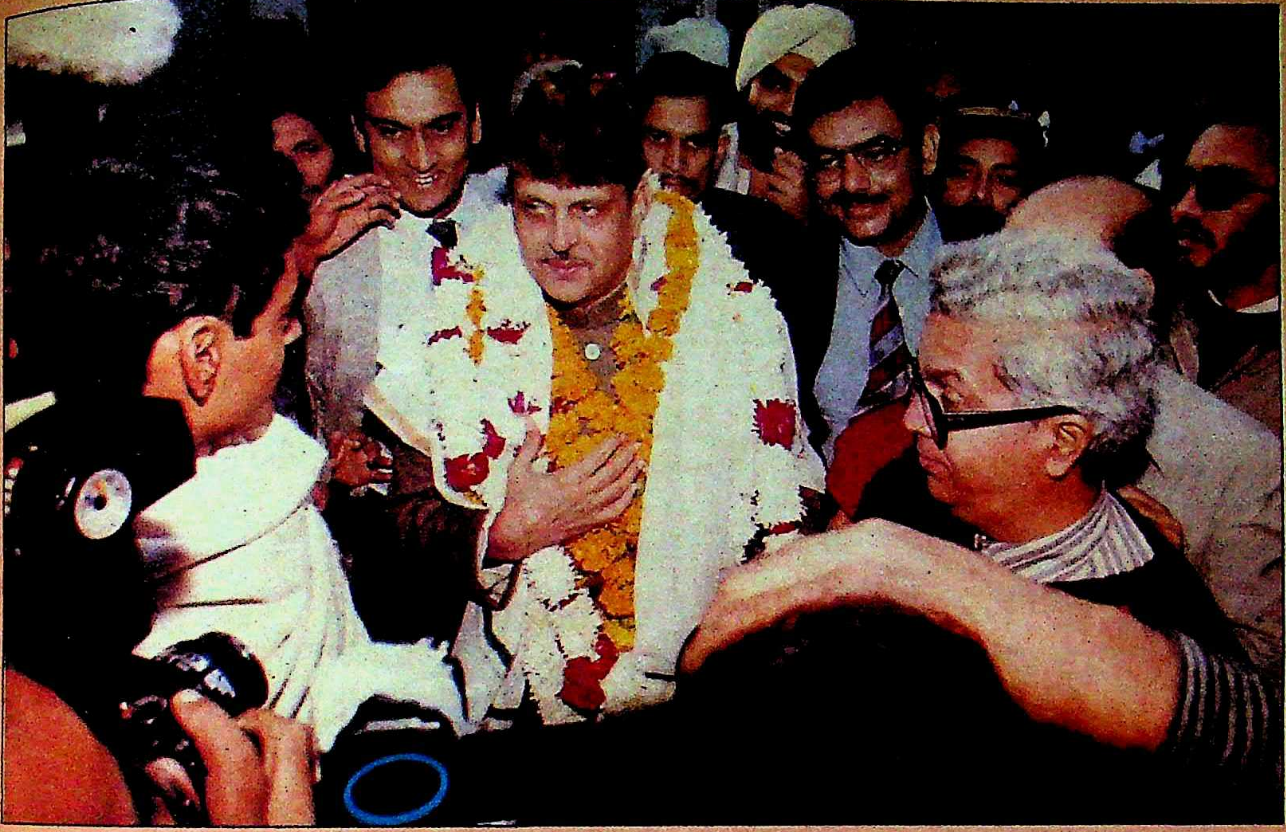

छाया : मनमोहन शर्मा

वीपी सिंह
चुनौतियों के चक्रव्यूह में

राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वीपी सिंह ने जो पिछले ढाई साल से मुहिम छेड़ रखी थी, उसमें वे कामयाब हो गये हैं। लेकिन जिन परिस्थितयों में वे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, उनको देखते हुए उनके सामने अपार चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं। ये चुनौतियां कौन सी हैं और क्या वे उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे ?

दिल्ली हतप्रभ है और विजेता किकर्तव्यविमूढ़ भारतीय लोकतंत्र की यह विचित्र बिसात थी। सम्मोहक सत्ता सुंदरी अपने नए राजपुरुषों के वरण के लिए विजयश्री की वरमाला तो लिए थी, लेकिन वह आशंकाओं के काले कपड़ों में लिपटी खड़ी थी। विजयोत्सव के श्रीगान और संदेह की थापों के बीच चल रही जुगलबंदी हर बार किसी नयी घोषणा की प्रतीक्षा में रुक कर फिर शुरू हो जाती थी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए सजी कुरसियां बार-बार लंबी प्रतीक्षा के बाद सूनी ही उठ जाती थीं। नये प्रधानमंत्री से लेकर नये मंत्रियों तक के चयन की शायद ही कोई प्रक्रिया हो जो एक या एक से अधिक बार न टाली गयी हो। तो वहीं नये मंत्रिमंडल के बंटवारे का शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिसके पीछे दर्जन भर गुप्त मंत्रणाओं-बैठकों, घात-प्रतिघात, दांवपेंचों व आधा दर्जन से ज्यादा आपसी झड़पों की कथा न छिपी हो और प्रधानमंत्री की कुरसी पर बैठने के बाद से विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई क्षण ऐसा नहीं है जो चुनौतियों के बीच घिरा न हो।

चुनौतियां : चुनाव परिणाम निकलने तक के समय को चुनौती काल मानने वाले एक बार फिर चकरघिन्नी खा गये। ढाई साल तक राजीव

CC 0. Domain. Haridwar

हुकूमत के खिलाफ चुनौती बने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारतीय जनमत ने बिना एक क्षण का मौका दिये खुद चुनौतियों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। पांच सौ पच्चीस नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के सदन में सिर्फ १४३ सांसदों वाले राष्ट्रीय मोर्चे (१४१ जनता दल, २ तेलुगूदेशम) की उन्होंने सरकार बनायी। उनको उसे वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी के दो विपरीत ध्रुवों के समर्थन की बैसाखियों पर चलाना है। वह भी तब, जब दोनों के समर्थन के बाद भी नयी सरकार सिर्फ १८ सांसदों के बारीक बहुमत पर टिकी हो और जनता दल के अंदर ही प्रधानमंत्री पद के अन्य महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों के साथ राजधानी में देश के आधा दर्जन से ज्यादा अरबपति व्यापारिक घराने पांच सितारा होटलों में अपनी झोलियां खोले डेरा डाले बैठे हों।

कांग्रेस में बोफोर्स के मुद्दे पर विद्रोह का झंडा बुलंद करने से लेकर फतेहपुर में नामांकन भरने तक यदि वीपी सिंह के लिए चुनौतियों की एक लंबी शृंखला थी, तो चुनाव परिणाम आने से प्रधानमंत्री बनने तक का सात दिनों का सफर अपने ही साथियों द्वारा बिछाये गये कांटों से भरा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह मंजिल अपने राजनीतिक चातुर्य से तय की या कुंडली में मौजूद राजयोग से, यह अभी भी एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन यही भारतीय जनमत और राष्ट्रीय राजनीति का सौंदर्य भी है। पर उसके आगे दूर तक फैले चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदना राजनीति के प्रकाण्ड महारथी के लिए ही संभव है। शायद यही नये प्रधानमंत्री के लिए असली अग्नि परीक्षा होगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अभी इस अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है।

अप्रत्याशित फैसला : देवीलाल शपथ लेते हुए

छाया : सुनील सक्सेना

इस चक्रव्यूह में घिरे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास सिर्फ दो ही हथियार हैं—एक, उनके साथ खड़ा व्यापक जन समर्थन और दूसरा उनका व्यक्तिगत राजनीतिक चातुर्य। प्रधानमंत्री पद के लिए शुरू के सात दिनों की दौड़ में वे अपने जन समर्थन के हथियार की क्षमता दिखा चुके हैं। जिसके चलते राजधानी में चंद्रशेखर और देवीलाल गुट तक के सांसद का 'माया' से कहना था, "यदि इस समय राजा को प्रधानमंत्री न बनाया गया, तो चुनाव क्षेत्र में जनता हमारे कपड़े तक फाड़ डालेगी।" तो वहीं प्रधानमंत्री पद के चुनाव से अड़तीस घंटों के अंदर जनता दल के बाकी तीन महारथियों (चंद्रशेखर, देवीलाल अजीत सिंह) के अचानक अपने-अपने समीकरण लड़खड़ा जाना विश्वनाथ प्रताप सिंह के राजनीतिक चातुर्य का एक ट्रेलर भर था।

नये प्रधानमंत्री के चयन के लिए दो दिन तक तीन दफा टलने वाली जनता दल संसदीय दल की बैठक के बाद एक दिसंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले ऐतिहासिक 'नाटक' से पहले तक चंद्रशेखर पूरी तरह आश्वस्त थे। पर देवीलाल द्वारा अपने सिर पर रखे 'राजमुकुट' को उसी क्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर रख देने के साथ ही जैसे पूरी बाजी ही पलट आयी। चंद्रशेखर के हाथों 'किंग' बनने वाले देवीलाल खुद 'किंग मेकर' बन गये और 'किंग मेकर' 'अध्यक्षजी' सभा में नाराजगी जाहिर कर खलनायक बन गये। और इस सबसे अलग विश्वनाथ प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए 'नो कमेंट' 'नो कमेंट' का जवाब देते और बधाइयां लेते रहे।

अर्धसत्य: विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रीय मोर्चे में एनटी रामाराव और रामकृष्ण हेगड़े से मिलने वाली संभावित चुनौतियों को यदि जनता खुद ही खतम कर चुकी थी, तो चंद्रशेखर के रूप में उभरी चुनौती को देवीलाल के 'अर्ध सत्य' ने पूरी तरह पस्त कर दिया था। इस हालत में ऊपर से यह नजर आना स्वाभाविक था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह फिलहाल अपने दल के अंदर की चुनौतियों से उबर कर पूर्ण विजेता की शक्ल में उभरे हैं। पर ठीक उसी समय राजधानी में यह मानने वाले राजनीतिक समीक्षकों की कमी नहीं थी कि देवीलाल को 'भीष्म पितामह' बना विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न केवल अपनी जड़ें खोद ली हैं, बल्कि जनता के बीच बने अपने कद को खुद छोटा कर लिया है जो कि उनकी असली और एकमात्र पूंजी है। "भारतीय जनमानस में हमेशा कुरसी पर बैठने वाले से बिठाने वाले का स्थान ऊंचा होता है, फिर चाहे वह भीष्म पितामह से लेकर चाणक्य हो या महात्मा गांधी से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो," जनता दल के एक महासचिव का 'माया' से कहना था। जब तमाम राजनीतिक समीक्षक और जनता दल के नेता इस बात को समझ रहे हों, तो यह भला कैसे संभव है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात को न समझते हों कि 'ताऊ' के सुपर भीष्म पितामही व्यक्तित्व की छाया और अहसान के तले इस क्षीण बहुमत सरकार को चलाना कितना चुनौती भरा काम है।

पर अगले दिन ही जहां सुबह अखबारों में देवीलाल के त्याग और भीष्म पितामह व्यक्तित्व के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री चुने जाने की विशाल पर 'बौनी' खबरें थीं, तो कुछ ही घंटों के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल को अपने साथ ही अपने नीचे उपप्रधानमंत्री की शपथ दिलवा कर स्थिति को बदल दिया। रही सही कसर शाम को देवीलाल की जगह उनके बेटे ओमप्रकाश चौटाला का हरियाणा की पैतृक 'कुरसी' पर खुद देवीलाल के हाथों 'राजतिलक' होने से पूरी हो गयी। निश्चय ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने जनता दल में मिलने वाली संभावित चुनौती देवीलाल से ज्यादा देवीलाल के उस 'भीष्म पितामह' कद से मिल सकती थी जो 'ताऊ' ने राजमुकुट अपने सर से उतार कर सिंह के हाथों सौंप कर हासिल किया था। पर दिल्ली में ही फिर सिंह के नीचे गद्दी ले लेने और उसी के साथ बड़े बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देने के साथ ही देवीलाल के व्यक्तित्व में जुड़ा अपार 'विदेह' तेज चौबीस घंटे में ही तिरोहित हो गया। यही तेज किसी भी प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होता है कि औपचारिक सत्ता के केंद्र होने के बावजूद अनौपचारिक या वास्तविक सत्ता किन्हीं दूसरे हाथों में हो।

इच्छा बड़ी थी : अरुण नेहरू

घटनाक्रम: चंद्रशेखर और देवीलाल के साथ अड़तालीस घंटों में घटित इन राजनीतिक घटना-दुर्घटनाओं के साथ ही अगले दिन लखनऊ में घट रहे हंगामेदार घटनाक्रम ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने उभर सकने वाली तीसरी 'संभावित चुनौती' अजीत सिंह को बुरी तरह धराशायी कर दिया। चंद्रशेखर और देवीलाल के बाद अजीत सिंह ही जनता दल में ऐसे नेता हो

सकते थे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने कभी किसी मोड़ पर चुनौती बन सकें। पर लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के सामने मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाने के बाद अजीत सिंह के राजनीतिक कद को भारी धक्का पहुंचा।

एक के बाद एक घटित ये तीन घटनाक्रम क्या सिर्फ संयोग मात्र थे? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाग्य ही इतना प्रबल था कि अड़तालीस घंटों के अंदर स्थितियां एक के बाद एक बदलती गयीं या विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरी राजनीतिक चतुरता से एक के बाद एक ऐसी बाजी ही खेल रहे हैं कि पासे उनके पक्ष में गिर रहे हैं? निश्चित तौर पर इस पर कोई एक मुश्त फतवा दे पाना फिलहाल अभी कठिन है। पर घटनाक्रम इस बात का संकेत अवश्य देता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह आगे आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे?

पर चुनौतियों का अपना कोई अंकगणित नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने और एकछत्र 'औपचारिक और अनौपचारिक' शक्ति केंद्र के रूप में अपने को स्थापित कर पाने की चुनौती से अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह जूझ ही रहे थे कि मंत्रिमंडल बंटवारे की चौतरफा 'मार' ने उन्हें घेर लिया। चुनौतियों का यह वह दूसरा चक्र है, जहां १४३ सांसदों के इस क्षीण बहुमत सत्ताधारी दल को अपने अंदर बैठे बिखरे ढेरों समूहों, गुटों, क्षत्रपों को सत्ता का उचित हिस्सा देकर संतुष्ट करने की 'विचित्र किंतु सत्य' किस्म की चुनौती पूर्ण जिमनास्टिक से होकर गुजरना पड़ता है। अजीत सिंह समर्थकों के अनुसार, "राजा साहब ने बहुत पहले ही भाई साहब (अजीत सिंह) को गृह मंत्रालय देने का वायदा किया था।" तो उधर चौधरी देवीलाल समर्थक ताऊ को उपप्रधानमंत्री के साथ ही गृहमंत्री पद दिये बैठे थे। वरिष्ठ पत्रकारों ने यह तक बताना शुरू कर दिया था कि देवीलाल के गृहमंत्री होने पर पंजाब समस्या सुलटना कैसे सरल हो जायेगा। उधर बीजू पटनायक विद्याचरण शुक्ल से लेकर एनटी रामाराव तक वरिष्ठ मंत्रालयों से लेकर उपप्रधानमंत्री तक के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे।

मंत्री बनाना अपरिहार्य : मेनका

मैराथन बैठकें : प्रधानमंत्री बनने के बाद से मंत्रिमंडल के गठन के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर से लेकर उड़ीसा और हरियाणा भवन तक चलने वाली मैराथन बैठकों के दौरों का ही नतीजा था कि पांच दिसंबर की सुबह कहीं जाकर नये प्रधानमंत्री का कार्यालय राष्ट्रपति भवन को नये मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के लिए सुबह ग्यारह बजे तैयारी करने का समय दे पाया। राष्ट्रपति भवन का अशोक हाल सजा का सजा ही रह गया। आखिरी वक्त प्रधानमंत्री के दफ्तर ने सूचित किया कि शपथ-ग्रहण समारोह अब सुबह नहीं शाम को होगा। वजह, जहां इस दौरान अजीत सिंह का गृह मंत्रालय न मिलने पर रूठ जाना था, तो वहीं दूसरी तरफ एनटी रामाराव का पी उपेंद्र को मंत्री बनाये जाने की जगह खुद को उप प्रधानमंत्री बनाये जाने का आग्रह था। रामाराव के लिए उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू इसके लिए देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह से सीधे-सीधे कह आये थे। उधर बीजू पटनायक ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त कोई और मंत्रालय न स्वीकारने का खुद उड़ीसा भवन में वीपी सिंह को बता दिया था। वीपी सिंह बीजू पटनायक को इस बाबत कोई वचन दिये बिना लौट आये। पर पूरी सतर्कता के साथ थोड़ी ही देर में उड़ीसा भवन यह खबर पहुंच गयी थी कि उड़ीसा के वरिष्ठ नेता रवि राय को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। पटनायक पहले ही यह कह चुके थे कि केंद्र में यदि आया, तो रक्षा मंत्री के रूप में ही आऊंगा वरना उड़ीसा को ही आगे संभालूंगा। रवि राय का नाम आते ही पटनायक गुट फिर हरकत में आया। आखिरकार समझौता हुआ कि फिलहाल न बीजू पटनायक आयें और न रवि राय, बल्कि वरिष्ठ नेता नीलमणि राउतराय पर सहमति बनायें। पटनायक खेमा राउतराय का पहले से ही पक्षधर था और इस तरह उड़ीसा का मसला फौरी तौर पर टल गया।

छाया : सुनील सक्सेना

ऐतिहासिक पहल : मुफ्ती मोहम्मद सईद

एनटी रामाराव के उपप्रधानमंत्रीपद के लिए सिंह ने 'सिद्धांत' को कवच बनाया। रामाराव को उन्होंने साफ कहा कि 'सिद्धांत रूप में यह पहले ही सहमति हो चुकी है कि राष्ट्रीय मोर्चा के महासचिव मंत्रिमंडल में यथावत लिए जायेंगे। उपेंद्र महासचिव के नाते मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। दूसरा सैद्धांतिक फैसला यह किया कि जनता दल को छोड़कर मोर्चा के बाकी सभी घटकों को एक-एक पद मिल रहा है। यदि तेलुगूदेशम को दो पद मिले तो असमगण परिषद, द्रमुक तथा कांग्रेस को आपत्ति होगी।

एनटी रामाराव सहित राष्ट्रीय मोर्चा के अन्य घटक दलों का संकट सुलझाने में वीपी सिंह को कोई परेशानी नहीं हुई। कांग्रेस-एस से एक ही सांसद केपी उन्नीकृष्णन चुनाव की छलनी से निकल कर लोकसभा में पहुंचे थे। इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में लेना ही था। द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने खाता ही नहीं खोला। इस हालत में द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने प्रतिनिधि का नाम देने को कहा गया। करुणानिधि ने सिंह को अपनी पार्टी के मुखपत्र 'मारसोली' के संपादक मुरासोली मरान का नाम भेज दिया। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान अपने उग्र हिंदी विरोधी लेखों के द्वारा राज्य की राजनीति में स्थापित होने वाले इस वरिष्ठ तमिल संपादक को दिल्ली में कुरसी देने के अलावा सिंह के सामने कोई रास्ता ही नहीं था। असम गण परिषद के प्रतिनिधि के रूप में दिनेश गोस्वामी के लिए एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री और असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल महंत खुद ही सिंह से बात कर के आये थे।

छाया : सुनील सक्सेना

लखनऊ में मान घटा : अजीत सिंह

असली चुनौती : पर मंत्रिमंडल गठन की असली चुनौती सिंह को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिली। मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ल और पुरुषोत्तम कौशिक दोनों ही मंत्रिमंडल में वरिष्ठ पदों के लिए दावे पेश कर रहे थे। वहीं तीसरी तरफ रघु ठाकुर का खेमा भी अपनी खुसुरफुसुर में लगा था। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी हाथ से निकल जाने के बाद अजीत सिंह गुट मंत्रिमंडल में अपने लिए 'ज्यादा हिस्सा' मांगने पर अडा था।

मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से अजीतसिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान को तो मंत्रिमंडल में लेना ही था। बदायूं से चुनाव जीतकर आने वाले शरद यादव मध्य प्रदेश के होने

के बावजूद उत्तर प्रदेश के ही कोटे में आते थे। यादव राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रिमंडल में जनता दल के एक प्रमुख आधार—पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यादव के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं था। इसी तरह मंत्रिमंडल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो मुख्य नाम सामने आये—मेनका गांधी और मृणाल गोरे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हारे जाने के बाद श्रीमती गोरे ने खुद ही अपना दावा पेश करने से इनकार कर दिया। इस हालत में बची अकेली महिला मंत्री मेनका गांधी भी संयोग से उत्तर प्रदेश से थीं।

इस तरह मंत्रिमंडल गठन के पहले दौर के पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश से वीपी सिंह सहित आधा दर्जन मंत्रिमंडलीय सदस्यों की सूची बन चुकी थी और रामधन, राजमंगल पांडे, जनेश्वर मिश्र, सत्यप्रकाश मालवीय, रसीद मसूद, सतपाल मलिक, जैसे आधा दर्जन से अधिक दावेदारों की फेहरिस्त मौजूद थी। इनमें शायद ही कोई ऐसा नाम हो जिसका नये मंत्रिमंडल में हक न बनता हो। पर इनको पहली सूची में शामिल करने का मतलब था कि पच्चीस सदस्यीय प्रारंभिक मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा (तेरह) मंत्री केवल उत्तर प्रदेश से हों और शेष १२ में पूरे देश के, बाकी २२ राज्य निपटा दिये जायें जो निश्चित ही वीपी सिह क्या, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। ज्ञातव्य है कि पहले दौर में वीपी सिह कुल पचीस मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले थे। पांच दिसंबर की शाम राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी नये मंत्रियों के लिए पचीस ही विशिष्ट कुरसियां सजायी भी गयी थीं। यह दीगर है कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए शपथ-ग्रहण समारोह के समय तक चल रही आंतरिक खींचातानी के चलते केवल सत्रह नये मंत्री ही शपथ ले पाये।

एक तरफ उत्तर प्रदेश की इस लंबी सूची को शामिल करने की हालत में नये मंत्रिमंडल का क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह ध्वस्त हो जाने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ इन नामों को शामिल न करने की हालत में क्षीण बहुमत जनता दल में असंतुष्टों की अचानक एक बड़ी फसल लहलहा जाने का खतरा भी था। प्रधानमंत्री-चयन की बैठक में नाराजगी जाहिर करके गये चंद्रशेखर की तीन साउथ एवेन्यू स्थित कोठी पहले से ही जनता दल का 'सार्वजनिक कोप भवन' बन चुकी थी। जनता दल में अब यह किसी से नहीं छिपा था कि जो भी नेता मंत्रिमंडल में उचित जगह न पाने या किसी अन्य कारण से वीपी सिह से असंतुष्ट होगा, वह सीधे इसी 'कोप भवन' में पहुंचेगा।

इसी खतरे से बचने के लिए वीपी सिह ने जहां उत्तर प्रदेश के इन बाकी दावेदारों को संतुष्ट करने के लिए सीधे खुद मिलकर या उनके नजदीकी लोगों के मार्फत यह समझाने का रास्ता चुना कि वे थोड़ी देर रुकें, वहीं कुछ को 'इससे ज्यादा महत्वपूर्ण' जिम्मेदारियां देने की बात कर संतुष्ट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ चंद्रशेखर खेमे के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने का रास्ता अख्तियार किया गया। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और चंद्रशेखर के विश्वस्त यशवंत सिन्हा को इसी के तहत मंत्रिमंडल में जगह दी गयी। पर सिन्हा को अंतिम समय तक यह नहीं बताया गया कि मंत्रिमंडल में उन्हें राज्यमंत्री पद का दर्जा दिया जा रहा है। शपथ-ग्रहण करने राष्ट्रपति भवन पहुंचे सिन्हा को समारोह शुरू होने के समय ही पता लगा कि घोषित होने जा रही सूची में उनका नाम राज्य मंत्रियों की सूची में है। फिर क्या था, तमतमाये हुए सिन्हा उसी समय उलटे पांव घर वापस लौट गये।

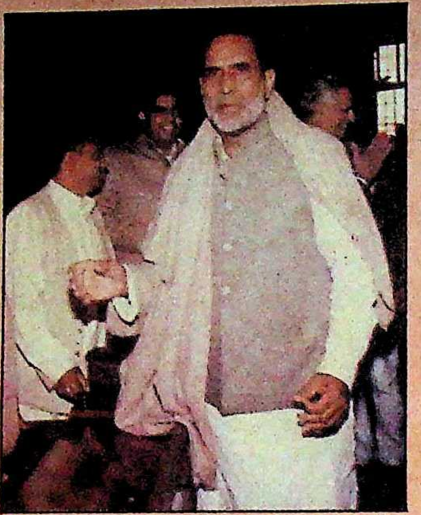

मेरे साथ धोखा हुआ : चंद्रशेखर छाया : सुनील सक्सेना

समझौते का रास्ता : पर इसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वीपी सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद जल्द ही छोड़ने की घोषणा करके पहले से नाराज चंद्रशेखर के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सुलह-समझौते का दरवाजा सार्वजनिक रूप से खोल दिया। यद्यपि इससे पहले वे अपने उपप्रधानमंत्री देवीलाल के मार्फत चंद्रशेखर को यह संदेश भेज चुके थे कि यदि चंद्रशेखर सरकार में शामिल होना चाहें, तो उनका स्वागत है। जिसके आधार पर ही करुणानिधि की बेटी की शादी में शामिल होने मद्रास पहुंचे चौ॰ देवीलाल ने संवाददाता सम्मेलन में भी यह घोषणा कर दी कि वे चंद्रशेखर को सरकार में शामिल होने के लिए मना लेंगे।

अपनी इसी मुहिम के तहत चौ॰ देवीलाल ने चंद्रशेखर से भोंडसी में मुलाकात भी की थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद 'ताऊ' अध्यक्षजी को प्रधानमंत्री-चयन की बैठक से पहले अपने द्वारा बोले गये 'अर्धसत्य' का 'सत्य' समझाने में असफल रहे। बताया जाता है कि इस मुलाकात में एक मौका ऐसा आया कि दोनों नेताओं के बीच आपसी बातचीत तेज कहा-सुनी में बदल जाने के बाद चंद्रशेखर कमरे से उठकर बाहर आ गये और अकेले मैदान में बिछी आराम कुरसी पर बैठ गये। उधर चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे चौ॰ देवीलाल चंद्रशेखर के कमरे में ही काफी देर तक अकेले बैठे रह गये। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री के चयन से पहले चल रही जोड़तोड़ के दौरान वीपी सिह और चंद्रशेखर के बीच मुकाबले से बचने के लिए यह फार्मूला निकाला गया था कि दोनों ही लोग चौ॰ देवीलाल के नाम का समर्थन करें। इसी आधार पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव से हटने के लिए तैयार हुए थे। पर एक दिसंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में चंद्रशेखर और वीपी सिह द्वारा चौ॰ देवीलाल का नाम प्रस्तावित और अनुमोदित करने के बाद सर्वसम्मति से नेता (प्रधानमंत्री) चुने गये चौ॰ देवीलाल ने अगले ही क्षण धन्यवाद देने की औपचारिकता के लिए बोलने खड़े होकर अपनी जगह वीपी सिह का नाम प्रस्तावित कर और उसी समय अजीत सिंह ने उसका अनुमोदन कर आधे सैकिंड के अंदर वीपी सिह को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया था। इस योजना को बैठक से पूर्व उड़ीसा भवन में हुए पांच वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के लंच के दौरान ही अंतिम शक्ल दी जा चुकी थी। पर चंद्रशेखर को अंतिम समय तक अंधेरे में रखा गया था। इस बाबत अगले दिन 'माया' से चौ॰ देवीलाल का कहना था कि उन्होंने चंद्रशेखर से झूठ नहीं बोला। बैठक के दिन ही उनकी चंद्रशेखर से मुलाकात हुई थी और वे कह आये थे कि "यदि उन दोनों (चंद्रशेखर और वीपी सिह) ने मुझे प्रधानमंत्री चुना, तो मैं यह सरकार नहीं चला पाऊंगा मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। हां मैंने

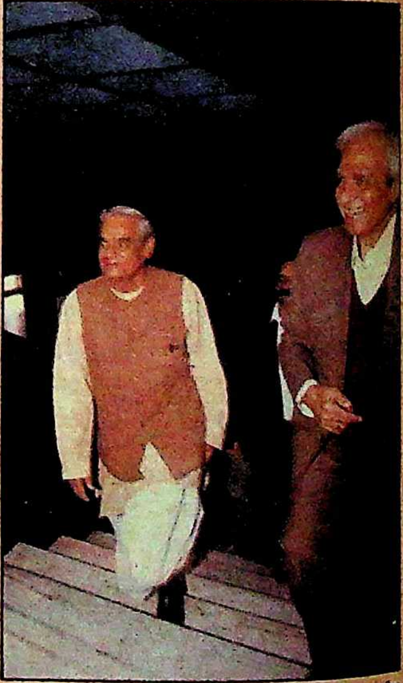

अनपेक्षित ऊंचाई की ओर : भाजपा नेता छाया : सुनील

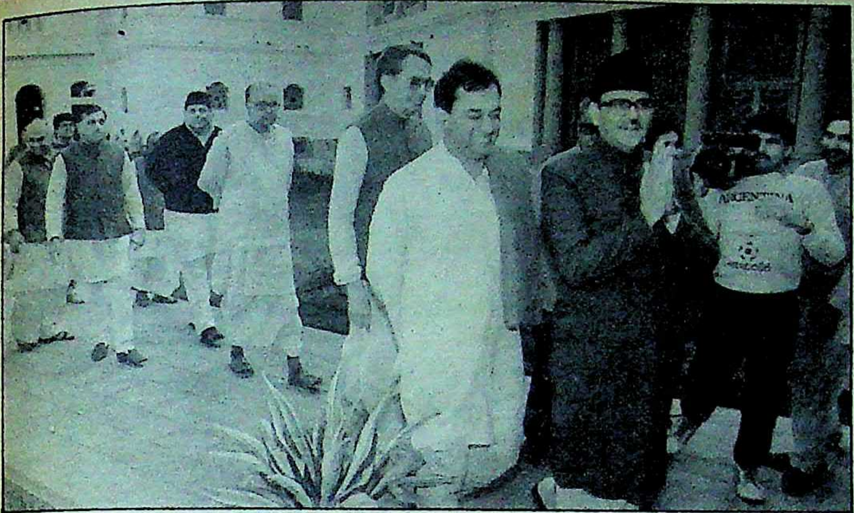

सबको पीछे छोड़ा: प्रधानमंत्री वीपी सिंह

छाया: मनमोहन शर्मा

इतना झूठ जरूर बोला कि उन्हें (चंद्रशेखर) यह नहीं बताया कि उसी समय इस्तीफा दे दूंगा।" जानकार सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर को उस समय यह दूर तक कोई अंदाज ही नहीं था कि देवीलाल सचमुच में उसी समय अपना पद सौंप देंगे। शायद इसीलिए देवीलाल के यह कहने पर चंद्रशेखर का जवाब था कि "जब इस्तीफा देंगे, तब देखा जायेगा, फिलहाल तो आप कुरसी संभालिए।" प्रधानमंत्री-चयन के बाद चौ० देवीलाल की चंद्रशेखर से मुलाकात का मकसद जहां इस 'अर्धसत्य' सुलह-सफाई देना था, वहीं वीपी सिंह की ओर से यह प्रस्ताव भी देना था कि वे यदि चाहें, तो उनकी तरह उपप्रधानमंत्री का पद संभाल लें या पार्टी अध्यक्ष हो जायें। चंद्रशेखर द्वारा उपप्रधानमंत्री पद के लिए साफ इनकार करने के बाद ही इस फार्मूले पर कोशिश शुरू हुई कि चंद्रशेखर पार्टी के अध्यक्ष हो जायें। नये मंत्रिमंडल के शपथ-ग्रहण समारोह के दौरान ही वीपी सिंह द्वारा इससे पहले कि चंद्रशेखर से देवीलाल के मार्फत चल रहे सुलह फार्मूले की खबर सामने आये, पार्टी अध्यक्ष-पद छोड़ने की घोषणा उनकी राजनीतिक शैली और रणनीति-संचालन की सिर्फ एक झलक भर देती है। जिसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आने वाले समय में जनता दल में उठनेवाले आपसी झगड़ों की चुनौती का वे किस तरह सामना करेंगे।

बाहरी चुनौती: पर चुनौतियां सिर्फ जनता दल के अंदरूनी घात-प्रतिघात तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बाहर से साथ चल रहे वाममोर्चे और भारतीय जनता पार्टी के आपसी द्वंद्व की भी हैं। इन दोनों के बीच जो मुद्दा सबसे पहले वीपी सिंह के सामने परेशानी का कारण बन सकता है, वह राम-जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद और सांप्रदायिकता है। जिसके लिए प्रधानमंत्री बनते ही वीपी सिंह का कहना था, "इसे आपस में मिलजुल कर दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हल किया जायेगा और यदि इससे कोई हल नहीं निकला, तो अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा।" एक तरफ जहां अपने को पूरी तरह तटस्थ रख वीपी सिंह ने खुद को किसी विवाद में पड़ने से बचाया है, वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्रालय सौंपकर भविष्य में खड़े होने वाले ऐसे किसी भी विवाद से बचने के लिए अपनी किलेबंदी की कोशिश की है। मुफ्ती मोहम्मद भारत के पहले मुसलमान गृहमंत्री होंगे। इसके बावजूद यह मसला नयी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।

सईद के गृहमंत्री बनने से जहां कश्मीर में पनप रही पृथकतावाद की चुनौती का सामना करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, वहीं पंजाब में वीपी सिंह ने खुद प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही स्वर्णमंदिर जाकर एक शुरुआत कर दी है। पर पंजाब की जनता द्वारा खुद भारी बहुमत से सांसद बनाये गये अकाली दल (मान) के छह सांसद और खासकर इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह की विधवा विमल खालसा और इंदिरा गांधी हत्याकांड के पूर्व अभियुक्त सिमरनजीत सिंह मान आगे क्या रुख लेंगे, यह अभी कहना कठिन है। पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का 'माया' से कहना था, "पंजाब में अब उठने वाली सबसे बड़ी चुनौती पिछले दिनों तेजी से पुलिस-प्रशासन के ध्वस्त हुए मनोबल को फिर से खड़ा करने की है।" उनका मानना था कि आतंकवादियों का खुले आम समर्थन करने और संरक्षण देने वाले उग्र अकाली नेताओं का भारी मतों से जीतकर सांसद बनने और राजीव सरकार द्वारा आखिरी दिन तमाम आतंकवादियों को दी गयी रिहाई से बदले माहौल में पुलिस और प्रशासन का मनोबल बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। नये गृहमंत्री के साथ वीपी सिंह पृथकतावाद और सांप्रदायिकता की चुनौती का सामना कैसे करेंगे, यह कहना कठिन है। यद्यपि इसके लिए जालंधर से सांसद चुनकर आये विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल का मानना है, "पंजाब की आधी समस्या तो सिर्फ राजीव सरकार के हटने भर से अपने आप खतम हो जायेगी।"

खाली खजाना: चुनौतियों की इस लंबी फेहरिस्त में एक खतरनाक चुनौती राजीव सरकार द्वारा छोड़ा गया खाली खजाना और आनेवाले दिनों में जबरदस्त आर्थिक संकट व मूल्यवृद्धि की है। राजधानी में प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि नयी सरकार ने फौरन मूलभूत और कठोर कदम नहीं उठाये, तो अगले साल की शुरुआत मे ही बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को भी चीरते नजर आयेंगे। इस चुनौती का सामना करने के लिए वीपी सिंह ने मधु दंडवते जैसे विद्वान और ईमानदार नेता को वित्त मंत्री बनाकर अपने प्रयासों का शुरुआती संकेत दे दिया है। पर अर्थशास्त्र के कठोर नियम तमाम दफा अपनी गति और दिशा को आसानी से नहीं बदलते हैं और वित्तमंत्री रह चुके वीपी सिंह खुद भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।

इसी के साथ ही जहां भूमि सुधार, बेरोजगारी, श्रमिक समस्याओं की मूलभूत चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं, वहीं विदेशी मोर्चे पर भी दृश्य कम परेशानी से भरा नहीं है। पर वीपी सिंह के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, वह खुद द्वारा खड़ी की गयी है और इसी से निपटना उनके लिए सबसे अधिक कठिन होगा। वह है—पिछले एक अरसे में भारतीय जनमानस में अपने प्रति जगायी गयी विराट अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती। निश्चय ही कांग्रेस छोड़ने के बाद से चुनाव जीतने तक की प्रक्रिया और अपने व्यवहार से वीपी सिंह ने आम जनता के मन में विराट अपेक्षाओं-आशाओं को जन्म दे दिया है। यह राजनीतिक सत्य है कि इस तरह किसी भी समाज में अचानक उपजी विराट अपेक्षाएं-आशाएं हमेशा यथार्थ और व्यवहारिकता से बहुत आगे होती हैं। अकसर एक मोहक सपने की तरह, जिसे पूरा करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ उनका पूरा न होना अचानक एक मोहभंग की स्थिति पैदा करती है जो प्रतिक्रिया का फिर अचानक दूसरा ध्रुव होता है। इक्कीसवीं सदी के सपने के साथ 'मिस्टर क्लीन' के मेकअप में आये तरोताजा राजीव गांधी के साथ मोहभंग की दुर्घटना कोई इतिहास की बात नहीं है और अब 'ईमानदार राजा' की छवि के साथ प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह अपने से बहुत तेजी से जुड़ी विराट जनाकांक्षाओं की भारी गठरी को कितनी दूर तक उठा पायेंगे, कहना कठिन है। पर इतना सच है कि यह जन आकांक्षाओं की गठरी जितनी बड़ी, जितनी भारी होगी, उसे उठाना उतना ही चुनौतीपूर्ण काम होगा। वह भी तब, जब वह सिर पर कांटों का ताज पहने अन्य चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हों।

—पुनीत टंडन

सन्नाटा: नेता पद के लिए देवीलाल के नाम का प्रस्ताव

छाया: सुनील सक्सेना

और वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ यों जीती

कहते हैं कि तूफान के बाद शांति खुद-ब-खुद स्थापित हो जाती है। आमचुनाव का तूफान खतम हो चुका है। राजा मांडा विश्वनाथप्रताप सिंह प्रधानमंत्री का ताज धारण कर चुके हैं। किंतु इस ताज धारण के पीछे घटनाओं का लंबा सिलसिला रहा है। प्रस्तुत है वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने तक की घटनाओं का रोजनामचा—

२६ नवंबर को शाम ५ बजे तक मतदाताओं ने अपना फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया था। विपक्ष में अनिश्चय का माहौल छाया हुआ था। चुनावी तस्वीर धूमिल नजर आ रही थी और वीपी सिंह ने लखनऊ में एक वक्तव्य देकर इस तस्वीर को और भी धुंधला कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कतई शरीक नहीं होना चाहता। यह वक्त सनसनी का था।

२६.नवंबर को चुनाव परिणाम आने की प्रक्रिया जारी थी। अरुण नेहरू और देवीलाल ने मौके की नजाकत को समझते हुई दिल्ली की ओर कूच किया। अरुण नेहरू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता ज्योति बसु से भेंटकर उनसे अनुरोध किया कि वे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने में सक्रिय सहयोग करें। ज्योति बसु ने अरुण नेहरू से साफ शब्दों में कहा कि वे और उनका दल जनता दल के नेताओं में वीपी सिंह को ही प्रधानमंत्री के पद पर देखने के इच्छुक हैं, किंतु भाजपा का रुख अड़चन डाल सकता है। इसके तत्काल बाद जद के चोटी के नेता और देश के स्वयंभू 'ताऊ' चौधरी देवीलाल ने घोषित किया कि राष्ट्रीय मोर्चे के नेतागण अपने नेता का चुनाव करने के लिए सूरज कुंड विश्रामगाह में मिलें।

२७ नवंबर तक राष्ट्रीय मोर्चे के समस्त दिग्गज नेता, जिनमें एनटी रामाराव, करुणानिधि असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत, चिमनभाई पटेल, बीजू पटनायक और वीपी सिंह शामिल थे, दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी नेताओं ने गहमा-गहमी से विचार-विमर्श शुरू किया। मोर्चे के कई नेताओं ने भाजपा और वामपंथी दलों से सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने वीपी सिंह को सुझाया कि वे मोर्चे की अगुवाई करें तथा रास्ते में चंद्रशेखर की अड़ंगेबाजी की कतई परवाह न करें।

भाजपा ने जद नेताओं से अपना रवैया स्पष्ट करने को कहा। भाजपा की दलील थी कि जद नेताओं ने चुनाव से पूर्व और चुनाव के दरम्यान ऐसे वक्तव्य दिये हैं, जिन पर भाजपा को सख्त एतराज है। सियासी धमाचौकड़ी जारी थी। वीपी सिंह के दावे को पुख्ता करने के लिए अरुण नेहरू ने साढ़े तीन बजे दिन में चंद्रशेखर के आवास पर मुलाकात की। नेहरू, चंद्रशेखर को किसी भी कीमत पर पटाना चाहते थे। किंतु चंद्रशेखर ने अरुण नेहरू को दोटूक जवाब देते हुए कहा, "अरुण, तुम्हारी उम्र उतनी नहीं है, जितनी मैंने राजनीति की है।" चंद्रशेखर ने नेहरू से प्रतिप्रश्न करते हुए कहा, "तुम ५४३ सदस्यीय लोकसभा में सिर्फ १४१ सांसदों के आधार पर किस प्रकार सरकार बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें राजनीति की इतनी-सी भी जानकारी नहीं है?" नेहरू चंद्रशेखर की बातों से हताश होकर वापस लौटे।

मोर्चे की संभावित सरकार का नेता कौन बने, इस पचड़े ने वीपी सिंह को भी दिग्भ्रमित-सा कर दिया। वीपी सिंह ने कहा कि इस मसले पर मैं अनौपचारिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, जब तक कि राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं की औपचारिक बैठक शुरू नहीं हो जाती। क्षुब्ध वीपी सिंह को एक कोने में ले जाकर आरिफ मुहम्मद खान ने उन्हें समझाते हुए कहा, "यदि आपने प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा नहीं ठोंका, तो अरुण नेहरू आपका साथ छोड़कर जनता के बीच चले जायेंगे और यह स्थिति आप और देश दोनों के लिए दुखदायी होगी।"

राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने नेतृत्व-समस्या को सुलझाने के लिए एक समिति गठित की, जिसमें रामाराव, अजीत सिंह, देवीलाल, वीपी सिंह, और अरुण नेहरू को रखा गया। इन सभी नेताओं ने भाजपा और वामपंथी दलों से बातचीत का सिलसिला बरकरार रखा।

किंतु इस बीच चंद्रशेखर ने नेतृत्व के मसले को अपने एक बयान से फिर सुलगा दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि यदि नये नेता का चुनाव सर्वसहमति से हो जाता है, तो यह बेहतर होगा, किंतु यदि नेतृत्व पाने की दौड़ शुरू होती है, तो इसमें मैं भी शरीक रहूंगा। चंद्रशेखर के अनुसार नये नेता-पद का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये ही किया जाना चाहिए। शाम को चंद्रशेखर ने देवीलाल से मिलकर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते हुए कहा, "मैं आपके (देवीलाल) नेतृत्व में काम कर सकता हूं। आप मुझसे उम्र और तजुर्बे दोनों में ही बड़े हैं। किंतु मैं किसी राजनीतिक नौसिखिये के साथ कतई काम नहीं करना चाहता। जब मैंने इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी, तब वीपी सिंह क्या हैं?"

भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे को दोटूक शैली में स्पष्ट कर दिया कि वे मोर्चे की सरकार को सशर्त

समर्थन देंगे। भाजपा ने इस सिलसिले में अपनी चार मांगे पेश कीं, जिनमें प्रमुख मांगें थीं—राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, सभी संप्रदायों के लिए एक विधि संहिता का निर्माण। अंत में भाजपा ने तय किया कि राष्ट्रीय हितों को देखते हुए वह मोर्चे की सरकार को फिलहाल बाहर से बिना शर्त समर्थन देगी।

पल-पल उतार-चढ़ाव के ऐसे माहौल में देवीलाल में भी अपनी हरियाणवी शैली में एक पत्ता फेंका। देवीलाल ने नेता-पद के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का फैसला किया। देवीलाल ने इस काम को अंजाम देने के लिए चंद्रशेखर और शरद यादव को आगे किया। देवीलाल अपने सुपुत्र ओमप्रकाश चौटाला और शरद यादव के इस गणित से कतई सहमत नहीं थे कि ६५ सांसद उन्हें (देवीलाल) नेता बनाने के लिए खुलकर समर्थन देंगे। शरद यादव और चौटाला की भरसक कोशिशों के बाद २६ सांसद हरियाणा भवन पहुंचे।

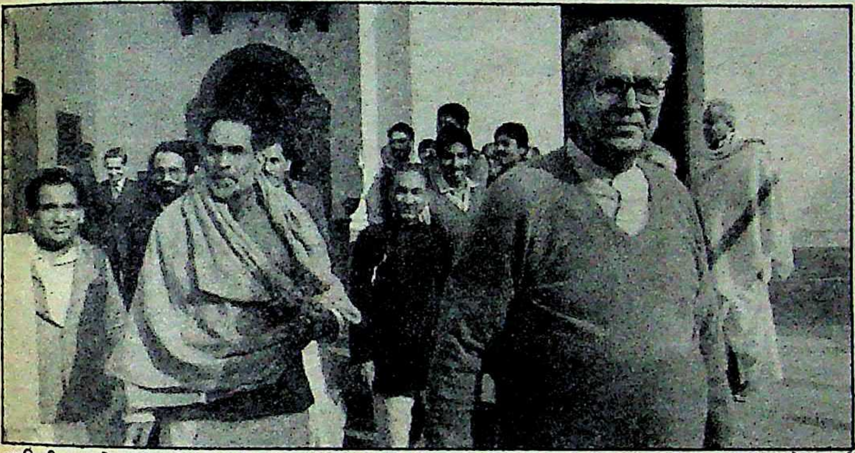

आखिरी दृश्य से पहले : नेता पद के चुनाव के लिए जाते हुए

छाया : मनमोहन शर्मा

२९ नवंबर को एनटी रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े, इंद्रकुमार गुजराल, रूठे चंद्रशेखर को मनाने के लिए उनके आवास पहुंचे। तीनों नेताओं ने चंद्रशेखर को सुझाया कि यह वक्त का तकाजा है कि हम लोग जनता के समक्ष एकता का भाव दर्शाएं। किंतु चंद्रशेखर ने अपनी सफाई देते हुए फिर कहा कि आप किस दम पर और वह भी महज १४१ सांसदों के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं? राष्ट्रीय सरकार के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है।

एनटीआर और वीपी सिंह दिन में ११ बजे बीमार चंद्रशेखर का हाल लेने उनके आवास पर पहुंचे। इसके कुछ ही मिनटों के बाद देवीलाल ने भी चंद्रशेखर के कक्ष में प्रवेश किया। देवीलाल ने वीपी सिंह और रामाराव की मौजूदगी में चंद्रशेखर को देखते ही प्रभावशाली अंदाज में कहा, "चंद्रशेखर, मैं तुमसे गुप्त वार्ता करना चाहता हूं।" इन क्षणों में चंद्रशेखर की बीमारी काफूर हो गयी। चंद्रशेखर ने वार्ता के दौरान देवीलाल से फिर अपना वही पुराना राग अलापते हुए कहा, "मुझे आपके साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है, किंतु मैं इस व्यक्ति (वीपी) के साथ कतई काम नहीं कर सकता।"

वीपी सिंह, अरुण नेहरू और अजीत सिंह को साथ लेकर भाजपा नेताओं से अशोक मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय पर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। वीपी सिंह ने भाजपा को आश्वस्त करवाते हुए स्पष्ट किया कि जनता दल भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी नहीं मानता।

३० नवंबर का दिन देवीलाल की बंद आख खुलने का दिन रहा। देवीलाल यह मुगालता पाले बैठे थे कि उनके साथ उप्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के ७१ सांसद हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री की कुरसी पर आसीन करवा सकते हैं। कुल मिलाकर बड़ी असमंजस की स्थिति थी। देवीलाल ने आखीर में अपनी राजनीतिक ताकत आंकने का मन बनाया। ३१ फिरोज शाह मार्ग पर शरद यादव के आवास पर देवीलाल ने एक बैठक आहूत करवायी। शरद यादव का दावा था कि इस बैठक में ४० सांसद शरीक हुए, जबकि अन्य सूत्रों का दावा है कि बैठक में मात्र १९ सांसद ही शामिल हुए। जो भी हो, बैठक में शरीक हुए सांसदों में ज्यादातर पहली बार चुने गये सांसद थे। शरद यादव ने इन सांसदों पर मनौवैज्ञानिक दबाव डालते हुए कहा कि यदि आप नेतृत्व पद की होड़ में वीपी सिंह के मुकाबले देवीलाल का चयन नहीं करते हैं, तो आप जहां से आये हैं, फिर वहीं लौट जायेंगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि स्वयंभू 'ताऊ' देवीलाल का कद प्रधानमंत्री पद की दौड़ ६ फुट से बढ़कर १२ फुट का हो गया। किंतु देवीलाल जल्दी ही यह समझ गये कि वे ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की कुरसी पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। जब इस गुपचुप बैठक की खबर वीपी सिंह के कानों में पहुंची, तब शरद यादव ने तुरंत पैंतरा बदल कर कहा कि बैठक के जरिये देवीलाल यह देखना चाहते थे कि वीपी सिंह का पक्ष कितना मजबूत होगा। शरद यादव के अनुसार देवीलाल ने यह बैठक वीपी सिंह के समर्थन में आहूत की थी।

जनता दल की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हरियाणा भवन में सुबह ७.३० बजे शुरू हुई। चंद्रशेखर चुनाव के बाद औपचारिक तौर पर पहली बार बैठक में शरीक हुए। देवीलाल, अजीत सिंह, हेगड़े, बीजू पटनायक, मधु दंडवते, जार्ज फर्नांडीस भी बैठक में सम्मिलित हुए। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वीपी सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक ने ऐसी खास बैठक में शरीक होना मुनासिब नहीं समझा। पत्रकारों को यह बताया गया कि वीपी सिंह की तबीयत खराब है।

मध्य रात्रि में अरुण नेहरू देवीलाल से मिले। देवीलाल ने उन्हें बताया कि वीपी सिंह को नेता मानने पर किसी को भी कतई एतराज नहीं है।

१ दिसंबर को हरियाणा के सांसद शरद यादव के आवास पर जमा हुए। शरद यादव ने उन्हें बताया कि वीपी सिंह के समर्थन के अलावा अब कोई चारा नहीं है। वास्तव में इन सांसदों को एक तरीके से रोके रखा गया था। वीपी सिंह और अरुण नेहरू ने टेलीफोन पर शरद यादव से जानकारी तलब की। शरद यादव ने उन्हें बताया कि ४० सांसदों की यह जिद है कि वीपी सिंह ही नेतृत्व का भार संभालें।

उड़ीसा भवन में दिन के २ बजे शुरू हुआ भारत के इतिहास की अविस्मरणीय घटना का अंतिम अध्याय। पूरे देश की निगाहें उड़ीसा भवन पर टिकी हुई थीं। वीपी सिंह, अजीत सिंह, हेगड़े, अरुण नेहरू और आरिफ मुहम्मद खान बड़ी बेसब्री से बैठक शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। देश की रहनुमाई करनेवाले का चयन लोकतांत्रिक विधि से होना था। बीजू पटनायक ने सवा दो बजे चंद्रशेखर को फोन कर कहा कि आप तत्काल ही उड़ीसा भवन चले आइये, बहुत जरूरी विचार-विमर्श होना है। चंद्रशेखर आनन-फानन उड़ीसा भवन पहुंचे। देवीलाल ने चंद्रशेखर को एक अलग कमरे में ले जाकर गुरुमंत्र दिया कि वीपी सिंह उनको (देवीलाल) नेता मानने के लिए सहमत हो गये हैं। देवीलाल ने आगे कहा कि वीपी सिंह नेता-पद के लिए खुद उनका नाम प्रस्तावित करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने देवीलाल को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं पूर्णतः आपके साथ हूं। आगे का घटनाक्रम यही था कि चंद्रशेखर ने देवीलाल का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया। देवीलाल नेता चुन भी लिये गये, किंतु चंद ही सैकंडों में देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम नेता-पद के लिए सुझा दिया, जिसके कारण वीपी सिंह दूसरे दौर में नेता चुने गये। चंद्रशेखर देवीलाल के इस व्यवहार से अवाक रह गये। चंद्रशेखर खुद को ठगा-सा महसूस करते हुए मन मसोस कर रह गये। इस प्रकार अंततः वीपी सिंह प्रधानमंत्री की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। ■

वीपी सिंह की करनी और कथनी

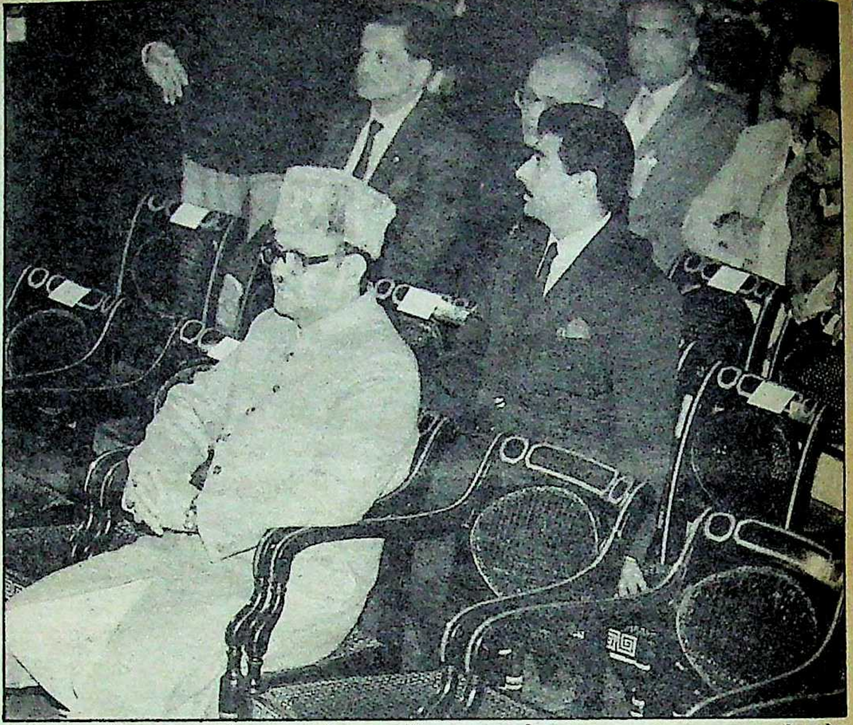

कुरसियां भरने का आधार योग्यता: अशोक हाल में शपथ-ग्रहण के समय

छाया: सुनील सक्सेना

सच है कि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। तभी तो १९८६ में पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान करनेवाला राजनीतिक आज देश का प्रधानमंत्री बना है। २ दिसंबर, १९८९ का अशोक हाल का दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता, जहां सत्ता में रहकर वीपी सिंह को मीरजाफर, सीआईए एजेंट आदि का खिताब देनेवाले, सत्ताच्युत हो जाने के बाद उसी 'मीरजाफर' को आदर देने के अदब से खड़े देखे गये। हाल तो यह था कि जिन लोगों ने वीपी सिंह को मंत्रालय छोड़ने पर मजबूर किया था तथा जिन लोगों ने सिंह की दूरदर्शन पर प्रस्तुति पर पाबंदी लगायी थी, वे अशोक हाल में बैठने के लिए कुरसी तलाशते फिर रहे थे। सिंह को बुरा-भला कहनेवालों के चेहरे उतरे हुए थे, फिर भी वे मुस्कराने का आडंबर करके अपने दुख और गुस्से को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तभी राष्ट्रपति आर वेंकटरमण हाल में पधारे, शपथ ग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू हुआ तथा राष्ट्रपति ने मुस्कराते हुए कांग्रेस-इ के बागी वीपी सिंह को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी।

जनता का प्रधानमंत्री: देश के आठवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री की हैसियत से भविष्य क्या है, यह तो अभी नहीं बताया जा सकता, किंतु जनमत ने जिस उत्साह और विश्वास के साथ वीपी सिंह को इस कुरसी तक पहुंचाया है, उसे देख-जानकर बीबीसी के संवाददाता की यह बात बिलकुल सच लगती है कि 'वीपी सिंह जनता के प्रधानमंत्री हैं।' चुनाव परिणाम आने तथा कांग्रेस-इ द्वारा सरकार न बनाने की मंशा का इजहार करने के बाद दिल्ली की सड़कों पर अपने भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह को देखने के लिए जनमानस का जो सैलाब उमड़ा था, उसे देखकर भी यही लगता था कि यदि राष्ट्रीय मोर्चा सिंह को अपना नेता न चुनता, तो इस देश का मतदाता एक बार फिर अपनी भूल पर पश्चाताप के आंसू बहाने को विवश हो जाता।

एक दिसंबर को ४ बजे शाम से ही दिल्ली की जनता में विकलता बढ़ रही थी। लोग यह जानने के लिए परेशान थे कि जनता दल का नेता कौन चुना गया या किसके चुने जाने की बात चल रही है। संसद की ओर स्कूटरों तथा मोटर-साइकिलों से भाग रहे दिल्ली के नवयुवक खुशी में झूम-झूम कर बस यही चिल्ला रहे थे 'बन गया भई बन गया, वीपी नेता बन गया', एक अजीब-सा उत्साह था। अंततः हुआ भी वही जो इस देश का मतदाता चाहता था।

एक अकेले व्यक्ति ने भारत के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। इस व्यक्ति ने अपने तीन साल के संघर्ष में देश की १०५ वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी के नेता को सत्ताच्युत करके देश में चल रहे नेहरू परिवार के शासन को पुनः जोरदार धक्का दिया। लोग हैरान हैं, यह जानने के लिए कि आखिर वीपी सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो इतने कम समय में वे कांग्रेस तथा राजीव गांधी से सत्ता छीनने में कामयाब हुए।

कोई जाने या न जाने वीपी सिंह की पत्नी श्रीमती सीता सिंह तो शुरू से ही इस बात से वाकिफ हैं कि उनके पति जितने भावुक, खामोश तबीयत और मृदुभाषी हैं, उतने ही कर्तव्य-परायण और सख्त भी। वे यदि कोई काम करने का एक बार प्रण कर लेते हैं, तो जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते, चैन से बैठते नहीं, बशर्ते वे इस बात से आश्वस्त हों कि जो कुछ वे कर रहे हैं या उन्हें करना है, वह अनुचित नहीं। वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति से की, जहां के बारे में उस समय यह धारणा थी कि यदि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बनना चाहता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में उसे सक्रिय होना पड़ेगा। बात सच भी है, क्योंकि समय के साथ यहां के बहुतेरे छात्र नेता केंद्र में मंत्री बने, जिसमें नारायण दत्त तिवारी भी एक हैं।

कर्तव्यपरायण: यही नहीं, कर्तव्यों के पालन में भी सिंह कभी पीछे नहीं रहे। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि दिखने में लचीला नजर आनेवाला उनका व्यक्तित्व उनके सोच तथा उनकी भावनाओं का प्रतिफल है। एक बार जब उनकी मां घोर बीमार पड़ी थीं, तो राजा ने कई रातें अपनी मा के पास बैठकर जागते हुए गुजारी थीं, ताकि मां को किसी तरह की तकलीफ न होने पाये। यही वह समय था जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थीं। उनकी लिखी हुई कई कविताएं 'धर्मयुग' में उस वक्त छपी भी थीं जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से जबरदस्ती बाहर किया गया था। इसके अलावा चित्रकला भी उनका एक पसंदीदा शौक है। वे जब भी सत्ता से बाहर रहे, उन्होंने चित्रकला तथा शायरी के सहारे ही अपना समय काटा। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में उन्होंने शब्दों को जिस तरह से पिरोया, वह उनके कविहृदय का परिचायक था जिसने छोटे, बड़े, अमीर, गरीब सब पर जादू-सा असर डाला। हालांकि आज भी बहुतेरे यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि वीपी सिंह ने अपना भाषण स्वयं लिखा था।

किंतु विडंबना यह है कि इतनी खूबियों के मालिक वीपी सिंह को उनके विरोधी कमजोर इरादों वाला व्यक्ति मानते हैं। विरोधियों के

अनुसार सिंह में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तथा अपने आप में वे खुद बहुत बड़ा विरोधाभास हैं। यही वजह है कि अहम तथा संगीन मामलों में सिंह खामोशी को तरजीह देते हैं। जबकि सचाई यह है कि १९८६ के ग्रीष्मकाल में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर वीपी सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था, उससे विरोधियों को धारणा बदल देनी चाहिए थी, क्योंकि '८६ का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था।

निर्णय लेने की क्षमता : उस फैसले से जहां यह पता चलता है कि वीपी सिंह में निर्णय लेने की क्षमता है, वहीं यह भी उजागर होता है कि जायज बात के लिए कुछ भी त्याग देने से वे सकुचाते नहीं। यही नहीं, उनके इस फैसले से उनके साथी आश्चर्य में पड़ गये थे, किंतु सबका यही मानना था कि इस्तीफा देकर सिंह ने अपना भविष्य अंधकार के सुपुर्द कर दिया है तथा उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है।

यही नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी तब सिंह से अपनी आखिरी मुलाकात में कहा था कि वे (वीपी सिंह) विरोध अथवा जनांदोलन छेड़ने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें चुपचाप सत्ता सुख भोगना चाहिए। उसी समय राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस-इ से अलग होकर उनका राजनीति से अंत हो जायेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे अपने पसंद का मंत्रालय लेकर वापस आ जायें। इस पर सिंह ने कहा था कि यह तभी संभव है जब राजीव गांधी कल्पनाथ राय जैसे लोगों के मुंह पर ताला लगवायें। सिंह की इस बात पर राजीव गांधी ने कहा था कि 'मैं देखूंगा' किंतु राजीव कुछ कर न सके और राजा तथा राजीव के बीच संबंधों में दरार पड़ गयी।

जब सिंह ने पद से इस्तीफा दिया था, उस समय वे भावुक जरूर हुए थे, किंतु अपने निर्णय पर अडिग थे। यही नहीं, उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा भी था, "यह सच है कि मैंने पार्टी से इस्तीफा देकर किसी-न-किसी के साथ अन्याय किया है, किंतु मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे देश-प्रेम अथवा राष्ट्र के प्रति ईमानदारी या वफादारी पर संदेह करे। मैं सदा इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा।" वीपी सिंह के इन शब्दों ने उन्हें तीन वर्षों तक तरह-तरह की मुसीबतों तथा हमलों का सामना करने पर मजबूर किया। किंतु भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिगुल उन्होंने बजाया था, उससे वे पीछे नहीं हटे।

मामूली संघर्ष नहीं : यह कौन नहीं जानता कि सत्ता के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष छेड़ा था, वह मामूली नहीं था। फिर उनके सामने मजबूरियां भी एक-दो नहीं थीं। न तो उनके पास वफादारों की मजबूत जमात थी, न कोई मंच और न ही पैसा। इन सब अभावों से जो दिक्कत उठानी पड़ रही थी, वह एकतरफ थी दूसरी ओर सत्ता से बगावत करने का कष्ट भी उन्हें सहन करना पड़ रहा था। स्थिति यह थी कि दिल्ली में १ राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर सत्ता पक्ष ने कड़ी निगरानी तैनात कर दी थी। इस्तीफा देने के बाद जब सिंह लखनऊ मेल से दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, तो उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे किसी से ढंकी-छिपी नहीं थीं। गाड़ी को तीन घंटा लेट सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि सिंह लखनऊ में आयोजित बैठक में समय पर न पहुंच पायें। यही नहीं, सरकार ने सिंह को हताश करने के लिए अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया था कि इस्तीफे के बाद से गाड़ियों तथा विमानों के रद्द होने तथा देर से चलने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वह तब तक चलता रहा जब तक वीपी सिंह ने किसी तरह फतेहपुर पहुंचकर चुनाव हेतु नामांकन पत्र भर नहीं दिया। यही नहीं, सिंह को निराश तथा कमजोर करने के लिए ही अरुण नेहरू तथा आरिफ मोहम्मद खान को उस समय कांग्रेस से निकाला गया था जब वे दोनों वीपी सिंह के साथ उनकी पहली जनसभा में हरिद्वार गये हुए थे। पार्टी की इस कार्यवाही पर सिंह आग बबूला हो गये थे तथा राजीव गांधी को भेजे गये अपने बारह शब्दों के तार में उन्होंने नेहरू तथा आरिफ के साथ किये गये आलाकमान के गलत निर्णय की भर्त्सना की थी। तब १४ अकबर रोड स्थित अपने निवास के लान में बैठकर अरुण नेहरू ने कहा था, "सचमुच सिंह अब नेता बन रहे हैं। लगता है अब वे संघर्ष करके दिखा देंगे।" नेहरू ने ठीक ही कहा था। वीपी सिंह सचमुच बागी हो चुके थे।

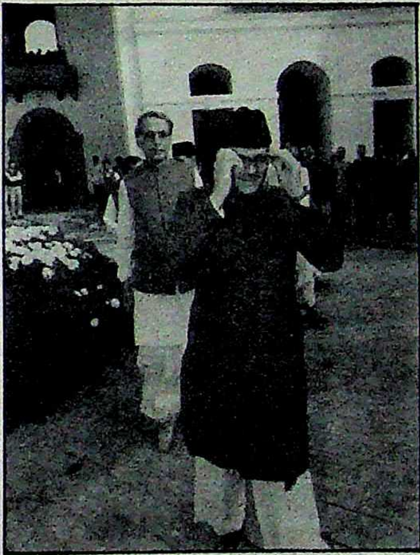

हालात पर बारीक नजर : वीपी सिंह छाया : मनमोहन

उल्लेखनीय है कि वीपी सिंह ने शुरू से ही कभी अपना आधार बनाने का प्रयास नहीं किया था। यहां तक कि १९७० में जब सिंह केंद्र में वाणिज्य मंत्री थे तब भी विद्याचरण शुक्ल तथा ओम मेहता ही उन पर छाये रहते थे। जनेश्वर मिश्र के अनुसार, "सिंह में यह काबिलीयत थी कि वे जनाधार खड़ा करके इलाहाबाद तथा फूलपुर जैसे चुनाव क्षेत्रों से विजयी हो सकें।" एमएस गुरुपदस्वामी बताते हैं, "लाल बहादुर शास्त्री ने वीपी सिंह को उनकी ईमानदारी तथा राजनीतिक परिपक्वता से प्रभावित होकर ही नवयुवकों में चुना था।" यही नहीं, शास्त्री तो सिंह को इतना मानने लगे थे कि सिंह को शास्त्री का पांचवां बेटा कहा जाने लगा था। शास्त्री से सिंह काफी हद तक प्रभावित भी हुए। जब सिंह के बारे में स्वर्गीय शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री से बातचीत की गयी, तो वे बेसाख्ता बोलीं, "राजाजी मेरे पति का बड़ा आदर करते थे। यही वजह थी कि ताशकंत जाने से पहले मेरे पति मांडा गये थे। तब राजाजी ने अपना अंगूठा काटकर अपने रक्त से मेरे पति के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। राजाजी की जितनी तारीफ की जाये कम है। मेरी नजर में तो राजाजी युधिष्ठिर हैं। बिलकुल युधिष्ठिर की तरह बुद्धिमान और न्याय-पसंद।"

राजनीतिक परिपक्वता : लाल बहादुर शास्त्री ने तो वीपी सिंह की राजनीतिक परिपक्वता से प्रभावित होकर ही उनका चयन किया था, किंतु बहुतेरे उनकी परिपक्वता से उस समय तक परिचित नहीं थे, जब तक संजय गांधी ने १९८० में उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। फिर जब १९८२ में वीपी सिंह ने डाकुओं के आतंक पर नियंत्रण न कर पाने तथा हत्याओं की नैतिक जिम्मेदारी अपने सिर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो लोग भौचक्के रह गये। जाहिर है, सत्ता सुख भोगनेवाला इतनी सरलता से नैतिक मूल्यों के चलते पद त्याग नहीं कर पाता। इस घटना ने सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित तथा लोकप्रिय बनाया।

विडंबना यह है कि वीपी सिंह के इस कदम से कांग्रेस-इ आलाकमान खुश नहीं हुए थे, अलबत्ता कांग्रेसी यह मानने लगे थे कि अब सिंह आस्तीन के सांप की भूमिका निभायेंगे। सभी कांग्रेसियों ने सिंह के इस कदम को 'धोखे' की संज्ञा दी थी। केवल केपी उन्नीकृष्णन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंह द्वारा उठाये गये कदम की सराहना करते हुए कहा था, "सत्ता में रहकर नैतिक जिम्मेदारी की समझ कायम रखना इतना आसान नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात है कि एक राजनीतिक ने मूल्यों की कद्र करते हुए सत्ता-सुख त्यागा है।"

इस्तीफा देने के बाद सिंह ने लखनऊ छोड़ दिया तथा अपना ज्यादा समय दक्षिण दिल्ली स्थित कैलाश अपार्टमेंट के निवास में लेखन तथा चित्रकला में व्यतीत किया। नारायण दत्त तिवारी के अतिरिक्त उस दौरान कोई अन्य नेता उनसे मिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा सका था। छह महीने बाद ही, जनवरी १९८३ में सिंह को

वाणिज्य मंत्री की हैसियत से पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आखिर क्यों? इसीलिए कि वीपी सिंह की 'साफ-सुथरी' छवि के कारण उनके प्रति जनता में उपजी सहानुभूति से कांग्रेस-इ नेतृत्व घबरा गया था। सिंह की ईमानदारी की चर्चा इस हद तक गर्म थी कि जून १९८३ में जब सिंह बेलग्रेड की यात्रा पर गये तथा एक सप्ताह बाद जब श्रीमती गांधी वहां पहुंचीं, तो दोनों बार यूगोस्लाबिया के मंत्रियों ने भारतीय पत्रकारों से यही प्रश्न किया था, "क्या आपके वाणिज्य मंत्री बहुत ईमानदार हैं? हमने सुना है कि वे आम राजनीतिकों जैसे नहीं।" कुछ दिनों बाद ही वाशिंगटन (अमरीका) के शासकीय अधिकारी ने सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा था, "वीपी सिंह भारत के एक उभरते हुए राष्ट्रीय नेता हैं जिनका राजनीतिक शिखर तक पहुंचना तय है।" कौन जानता था कि एक दिन उसकी यह भविष्यवाणी सच होकर रहेगी?

इसके बाद वीपी सिंह को वाणिज्य मंत्रालय से हटाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस-इ कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, यह गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पायी। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि सिंह की देश-विदेश में बढ़ती ख्याति से प्रणव मुखर्जी तथा आरके धवन जैसे लोग काफी चिंतित हो उठे थे तथा ऐसे ही लोगों की कहा-सुनी के चलते उन्हें (वीपी सिंह) उठाकर प्रदेश में फेंका गया। सिंह के विरोधियों को पूरा यकीन था कि सिंह उत्तर प्रदेश में उतनी सरलता से जम नहीं पायेंगे। किंतु उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर पानी पड़ा। चुनाव आये। सिंह ने अपनी क्षमता का परिचय दिया तथा उत्तर प्रदेश की ८५ में से ८३ लोकसभा सीटें कांग्रेस-इ के खाते में गिरवायीं। नतीजतन, पुरस्कारस्वरूप सिंह को वित्त मंत्रालय थमाया गया। लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध करना बंद नहीं किया।

शक के घेरे में : ये वे दिन थे जब वीपी सिंह की हर हरकत पर शक किया जाता था। वे बार-बार सफाई देते कि न तो वे बच्चन बंधुओं के विरुद्ध हैं न ही किसी खास व्यापारिक घराने के, फिर भी उन पर शक किया जाता रहा। उनके अधिकारी—भूरे लाल, विनोद पांडे और वाधवन, सब—सही और सख्त व्यक्ति थे, किंतु उन पर आरोप लगाया गया कि वे प्रधानमंत्री (राजीव) के मित्रों के प्रति दुर्भावपूर्ण रुखवाले हैं। वीपी सिंह के प्रशंसक सचिव एस वेंकटिरमन मंत्रिमंडल-सचिवालय के एकमात्र अधिकारी बचे थे जिन पर अब संदेह किया जा रहा है कि वे मंत्रिमंडलीय गतिविधियों में प्रधानमंत्री भवन और अंबानी तथा बच्चन बंधु जैसे मित्रों पर नजर रखे हुए थे। आखिर, चेतावनी के पलीते दागे ही गये। पहली जुर्रत कलकत्ता में आरपी गोयनका ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह कहकर दिखायी, "जिस तरह से व्यापारिक घरानों पर छापे मारे जा रहे हैं, उससे राजीव गांधी नाराज हैं।" कहा जाता है कि अंबानी और बच्चन बंधु राजीव गांधी के कान भर रहे थे, "वीपी सिंह के असली निशाने आप (राजीव) ही हैं, हमें तो इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने आपके चारों तरफ एक ठोस सुरक्षात्मक घेरा बना रखा है।" यह बात कहां तक सच थी?

वित्त मंत्रालय में अपने अंतिम दिन तक और बाद में भी सिंह बार-बार कहते रहे कि उन्होंने कभी बच्चन बंधुओं के खिलाफ जांच के आदेश नहीं दिये, न ही रिलायंस के मामलों में ही कोई जांच करायी, बल्कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में लगातार कई लेख छपने के बाद एक सामान्य ढंग की ही जांच शुरू की गयी। पर राजीव गांधी के इर्द-गिर्द के अधिकांश लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। वे सिंह के खिलाफ शिकायतें करते रहे। फिर भी, कई बार हेरफेर होने पर भी, सिंह मंत्रिमंडल में बने रहे। उनके चरित्र पर आक्रमण तो १९८५ में शुरू हुए। आरोप लगाया गया कि वे सर्वोच्च पद की आकांक्षा रखते हैं और राजीव गांधी को कुरसी से हटाने की साजिश कर रहे हैं। अचानक डहिया ट्रस्ट तथा सिंह की अन्य कथित कब्जेवाली संपत्तियों के किस्से 'रविवार' (अब बंद) में छपने लगे। क्षुब्ध होकर सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर बहुत ही तीखी बातें कह डालीं। तब राज्य विधानसभा के गलियारों में ऐसी कानाफूसी चल रही थी कि ये बातें नयी दिल्ली के आकाओं के इशारे पर कही गयी हैं। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजीव गांधी के करीबी तरफदार वीरबहादुर सिंह से सदन में सवाल भी पूछे गये। जो बिलगाव दो साल बाद हुआ, वह राजभवन में तभी स्पष्ट हो गया था जब राज्यमंत्री जफरअली नकवी और कुछेक दूसरे विधायकों ने विक्षुब्ध वीपी सिंह के साथ बैठकर, उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए, हाईकमान को कार्रवाई करने की चुनौती तक दे डाली थी।

अपने अध्यापक के साथ वीपी सिंह छाया : मनमोहन

प्रहारों का जवाब : क्षुब्ध सिंह ने जिस तेजी से अपनी विश्वसनीयता और ईमानदारी पर हुए प्रहारों का जवाब दिया, वह अपनी स्वच्छ छवि हर कीमत पर बनाये रखने की उनकी चिंता का परिचायक था। राजीव गांधी के बयानबाज दोस्तों ने प्रचार माध्यमों में, लोकसभा में और कुछ चुने हुए सांसदों के जरिए जितने भी प्रहार किये, वीपी सिंह ने उन सबके जवाब अपेक्षाकृत अधिक गरमजोशी से दिये। पर उन्होंने बगावत का कोई संकेत जाहिर होने नहीं दिया, न ही कभी ऐसा लगा कि उन्हें इतना उत्तेजित किया जायेगा कि वे पार्टी छोड़ देंगे। पर तभी फेयरफैक्स के मामले में वीपी सिंह की खिंचाई करते हुए दिनेश सिंह ने वह भाषण दे डाला जिससे अरुण सिंह इतने बौखला गये कि राजीव गांधी से सीधे पूछ बैठे, "दिनेश सिंह को वीपी सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है?" उस भाषण का ही प्रभाव था कि वीपी सिंह ने कांग्रेस-इ से नाता तोड़ने का फैसला किया।

२४ जनवरी, १९८६ को वीपी सिंह का विभाग बदल दिया गया। वे रक्षामंत्री हो गये। उसी दौरान राजीव गांधी ने बोट क्लब की बैठक में अपना मशहूर मुहावरा छेड़ा, 'मीर जाफरों को नानी याद करा देंगे।' उस बैठक में वीपी सिंह को खास तौर से लाया गया और अगली कतार में बिठाया गया था। वहां वीपी सिंह के व्यवहार से उनके शत्रु स्वतः शांत हो गये। उनका ख्याल था कि वीपी सिंह पानी-पानी हो रहे हैं और अब इस हद तक बदनाम हो जायेंगे कि इनके सामने तनहाई में कैद रहने के सिवा दूसरा विकल्प ही नहीं रह जायेगा। कारण, वे कभी नेता के सामने अकड़ते दिखे ही नहीं। वे कभी आक्रामक नहीं हुए, सिर्फ सावधानी से अपनी छवि बचाते रहे हैं। वह एक बड़ी रणनीति थी जिसे कोई ताड़ नहीं सका। देशवासियों की निगाह में वे एक ऐसे ईमानदार, सराहनीय राजनेता के रूप में उभर रहे थे जिसे राजीव गांधी के आसपास के गंदे लोग खामखाह दबा रहे थे। दूसरी ओर राजीव गांधी का प्रभामंडल धूमिल हो रहा था।

सहनशक्ति : निजी वार्तालाप में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी राजीव गांधी पर गुस्सा नहीं किया। वे यही कहते रहे, "राजीवजी के अंतरंग मित्र इतनी गरमजोशी के साथ खामखाह हमले क्यों किये जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।" उनसे कई बार पूछा गया, "राजीव गांधी तरफदारों के हमले का जवाब देने के लिए क्या आप बच्चन बंधुओं के खिलाफ कोई सबूत रखे हुए हैं?" उनका नपातुला जवाब होता "मैंने कभी किसी जांच के आदेश दिये ही नहीं।" अब लगता है, वे सच ही बोल रहे थे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है न! राजीव के करीबी लोगों को एक खौफ सताने लगा था, लिहाजा वे वीपी सिंह को सिलसिले से काट देने की जुगत में लगे हुए थे। अपनी करनी-करतूत की कालिमा और राजा मांडा के तेवर से बदहवास कल्पनाथ

खुला दरबार: प्रशंसकों से घिरे वीपी सिंह

छाया: सुनील सक्सेना

राय, केके तिवारी, रत्नाकर पांडे जैसे महारथी ताल ठोंककर वीपी के पीछे पड़ गये। वीपी को सिलसिले से काटने के लिए क्या नहीं किया गया? उनके खिलाफ क्या नहीं कहा गया? खतम करने की बात तक खुले आम कही गयी।

उसी दौरान दिल्ली के साहित्यिक हलकों में यह व्यंग्य चल पड़ा था, "तीन जनखे ताली बजा-बजा, मटक-मटक कर गाली गा रहे हैं और सूत्रधार जुगाली कर रहा है।" राजीव गांधी भले उस गाली अभियान के संचालक न हों, लेकिन राग वही अलाप रहे थे, हां कुछ परिमार्जित लहजे में। अभियान में रंगत तो तभी आयी थी जब उन्होंने कहा था, "नानी याद करा देंगे।"

जब हद हो चली, तो वीपी भी हरकत में दिखे। शुरुआत उन्होंने एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों के सौदे की जांच के आदेश देकर की और यह बात आम जनता के बीच रख दी। अगर यह औचित्य का उल्लंघन हुआ, तो ज़ानबूझ कर हुआ। इरादा बनाकर वीपी ने राजीव को कार्रवाई करने की चुनौती दी थी। और वहीं राजीव जाल में आ फंसे। जनता के मन में जहां यह बात जा बैठी कि बहुत ईमानदार होने के नाते ही राजा ने जांच के आदेश दिये हैं, वहीं राजीव ने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि वीपी के सामने, सिवा इस्तीफा देने के, कोई रास्ता ही नहीं बचा। और जब उन्होंने फौरन इस्तीफा दे मारा, तब हमदर्द जनता जनार्दन की छाती हमदर्दी से फूल गयी। लोकमानस में वीपी एक मसीहा की मानिंद उभरे और राजीव गांधी—भ्रष्ट लोगों की पीठ ठोंकनेवाले एक दमनकारी की शक्ल में।

रातोरात लोकनायक बने: बंबई में 'टॉक आफ द टाउन' रेस्तरां के ऊपर मैरिन ड्राइव चुदसम्मा का बहुचर्चित बैनर चमका, "गांधी के देश में ईमानदार की खैर नहीं।" वीपी सिंह रातोरात लोकनायक हो गये, भले इसके लिए वे सांसत में रह संघर्ष करते रहे हों। उधर राजीव गांधी मानो बेनकाब हो गये हों। राजीव के यारों ने यह बात समझने में थोड़ी देर कर दी। गोपी अरोड़ा वीपी को समझाने-मनाने के लिए भेजे गये। पर इसके पहले ही विदग्ध राजनीतिज्ञ वीपी यह तय कर चुके थे कि उनका स्थान राजीव के खेमे में नहीं है और उनकी जमापूंजी मात्र उनकी साख है, उनकी लोकछवि है।

वीपी ने उसका भरपूर और सटीक उपयोग किया। तीन साल के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि एक तनहा शख्स राजसत्ता हासिल कर सकता है, बशर्ते वह एक ईमानदार व्यक्ति होने की साख जनमानस में जमा दे। इस साख से, वीपी सिंह से संबंधित सारे विरोधाभास ढंक गये और अपनी संजीदगी की बदौलत वीपी ने इतिहास बना लिया। इससे भी आगे बढ़ वे यह दिखा गये कि खुले तौर पर भारतीय बनकर वे अकेले दम पर भारत को जीत सकते हैं। इनकी गलतियां-कमजोरियां चाहे जितनी और जो-जो रही हों, उन्होंने दिखा दिया है कि वे बेजोड़ हैं।

इतना ही नहीं, वीपी सिंह ने अपना वह व्रत भी पूरा कर दिखाया जो उन्होंने साउथ ब्लाक स्थित रक्षा मंत्रालय के रंगीन कक्ष के सामने खड़े होकर लिया था। उनके साथ जो सलूक हो रहा था, उससे वे आजिज आ गये थे। जब उन्हें बताया गया कि राजीव और उनके दोस्त उनका (वीपी का) राजनीतिक वजूद खतम करने पर तुल गये हैं, तब अपने पूरे कद से तनते हुई वीपी सिंह ने कहा था, "कोई नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाग्य कोई नहीं बना सकता, विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक प्रारब्ध विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा ही लिखा जायेगा।" और उन्होंने सचमुच यह कर दिखाया।

—विजय दत्त

कुछ रोचक भाषण

पोस्टरों, बंदनवारों, तोरणद्वारों, टेपांकित गानों और वीडियो फिल्मों ने तो चुनाव-प्रचार को रंगारंग बनाया ही, नेताओं ने तरह-तरह के आख्यानों और रूपकों का पुट देकर अपने भाषणों को भी काफी मनोरंजक बनाया। कांग्रेसियों ने विपक्षी एकता और नेता के रूप में उभरे वीपी सिंह पर व्यंग्य करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। वे कहते थे कि कल्पना कीजिए ऐसे दूल्हे की, जिसके पास अपना एक भी कपड़ा नहीं, क्योंकि शादी हड़बड़ी में तय हुई है। इसलिए किसी ने दूल्हे को टोपी दे दी, किसी ने कुरता। किसी ने पायजामा दे दिया, तो किसी ने बंडी। जब वह इस तरह उधार के कपड़ों में सजा मंडप में पहुंचा, तो सबने एक-एक करके अपने कपड़े मांगने शुरू कर दिये। इसके बाद कांग्रेसी जनता से पूछते थे, "क्या आप ऐसा राजनीतिक कैबरे देखना पसंद करेंगे?"

पीलीभीत से लोकसभा के लिए जद प्रत्याशी श्रीमती मेनका गांधी ने महाभारत चाहे न पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने सीरियल जरूर देखा होगा। वे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिशुपाल वध की कथा सुनाती थीं। वे कहती थीं कि शिशुपाल की मां को कृष्ण ने वचन दिया था कि वे शिशुपाल के सौ अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन इसके बाद वे उसे माफ नहीं करेंगे। परिणाम यह हुआ कि ज्योंही शिशुपाल ने अपराधों की सीमा लांघी, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। कांग्रेस के भी आपने सौ अपराध माफ किये हैं, लेकिन उसके अपराध करने का क्रम आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप अब जद के चुनाव चिह्न रूपी सुदर्शन से कांग्रेस का वध कर दें।

वीपी सिंह जब इलाहाबाद की एक सभा में पांच घंटा विलंब से पहुंचे, तो उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, "मैं पांच घंटा देर से पहुंचा हूं, लेकिन आपने कांग्रेस को पांच साल तक झेला है, इसलिए मैं आपके इस धैर्य को समझता हूं। आपने पांच घंटा मेरा इंतजार करके यह सिद्ध कर दिया कि अब कांग्रेस का अंत हो गया है।"

इलाहाबाद में ही, यहां की सीट के लिए खड़े हुए जद प्रत्याशी जनेश्वर मिश्र एक और ही रोचक भाषण देते थे। वे कहते थे, "स्व० हेमवती नंदन बहुगुणा मेरे को छोटे भाई की तरह मानते थे। वे मेरे राम थे और मैं उनका लक्ष्मण। इसलिए कांग्रेसी प्रत्याशी श्रीमती कमला बहुगुणा मेरी आदरणीय भाभी हैं। बहुगुणाजी के मरने के बाद कांग्रेसी रूपी रावण ने मेरी आदरणीय भाभी का अपहरण कर लिया है, जिससे बहुगुणाजी की आत्मा बड़ी बेचैन है। मैं २२ नवंबर (मतदान के दिन) को इस कांग्रेसी रावण का वध करके अपनी भाभी को मुक्त कराऊंगा। आप मेरा समर्थन कीजिए।"

■

अमेठी

बूथ कब्जियाने की हिंसक शैली

जिन लोगों को ७, रेसकोर्स दिल्ली का सुरक्षा तामझाम देखने को नहीं मिला है, उन लोगों को २२ नवंबर को अमेठी में होना चाहिए था। अमेठी की सीमा में घुसने से पहले बदस्तूर वाहनों की तलाशी हो रही थी और पूरा क्षेत्र छावनी बना हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को बमों और अस्त्र-शस्त्रों से भरी जीपें लिये घूमने की पूरी आजादी थी। इसी आजादी का परिणाम है कि अमेठी की धांधली देश-विदेश में चर्चित हुई और जद के प्रत्याशी डा० संजय सिंह को गोली का निशाना बनना पड़ा।

बूथ पर हमले के बाद मतदाता नदारद छाया : मनमोहन शर्मा

इस हिंसक माहौल की तैयारी का किस्सा १२ नवंबर से शुरू होता है। उस दिन अमेठी संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर की चुनाव सभा में जब राजीव गांधी साढ़े आठ बजे पहुंचे, तो उन्हें सुननेवालों की कुल भीड़ तीन हजार के आसपास थी। उसमें भी एक बड़ा हिस्सा सुरक्षाकर्मियों का था। वैसे तो भीड़ दस हजार के आसपास जुटायी गयी थी, लेकिन राजीव गांधी के थका देनेवाले इंतजार ने भीड़ को छांटना शुरू कर दिया था। बचे वही लोग थे जो बसों में लाद-फांदकर के लाये गये थे।

जिस अमेठी में राजीव गांधी ने विकास की नदी बहा रखी थी, उसी अमेठी संसदीय क्षेत्र के सलोन कस्बे में जब १४ नवंबर को विश्वनाथ प्रताप सिंह पहुंचे, तो उनको सुननेवालों की कमी नहीं थी। ये दो ऐसे दृश्य थे, जिनसे राजीव गांधी का माथा ठनका और पहली बार उन्हें लगा कि कुरसी हिल रही है। जायस, गौरीगंज और नंदमहर की सभाओं से विश्वनाथ प्रताप सिंह की हवा अमेठी के गौरीगंज डाक बंगले में पसरे सतीश शर्मा और लखनऊ में बैठे नारायण दत्त तिवारी को छूते हुए सीधे राजीव तक पहुंची थी। इस हवा की प्रलयंकारी शक्ति को देखकर कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मच गया। जहां बहुमत में आने का दावा किया जा रहा था, वहीं लगने लगा कि अपना नेता कहीं १९७७ के इतिहास को दुहराये जाने का शिकार न हो जाये। १९७७ में इंदिरा गांधी रायबरेली में राजनारायण से पराजित हो गयी थीं। बस इस चिंता ने देश की सारी हाटलाइनों को अमेठी और राजीव गांधी के बीच जोड़ दिया। तय किया गया कि अमेठी में बाहुबलियों की ताकत झोंक दी जाये—किसी भी कीमत पर नेता को विजयी बनाना है। तैयारी के लिए माखनलाल फोतेदार दिल्ली से उड़कर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान गौरतलब बात यह हुई कि गोरखपुर के बलशाली नेता हरिशंकर तिवारी कांग्रेस में ससम्मान शामिल हो गये।

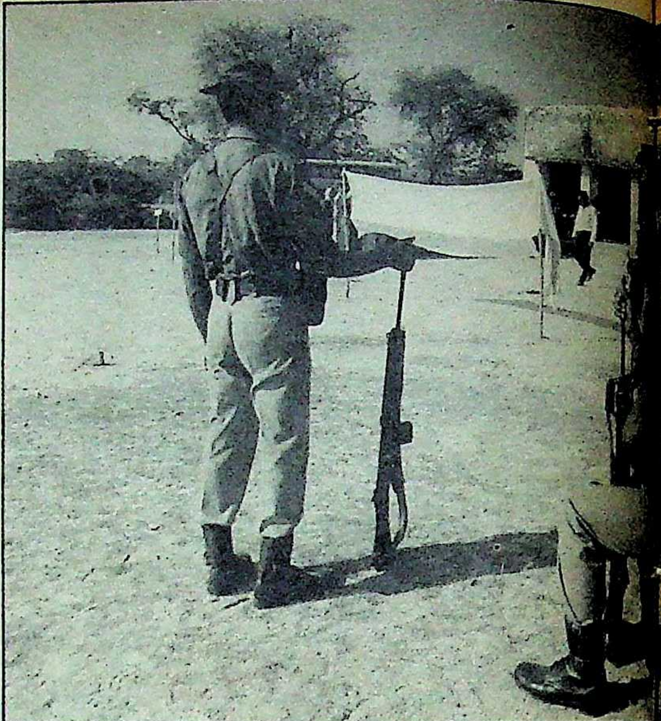

मतदाता कम, पुलिस ज्यादा : अमेठी का एक मतदान केंद्र छाया : मनमोहन शर्मा

इधर खबरें निकलने लगीं कि अमेठी में 'राजीव जिताओ, संजय हराओ' की मुहिम के लिए बाहुबलियों की टोलियां पहुंच रही हैं। २२ नवंबर के पहले ही अमेठी की हवा में उठ रही हिंसा की गंध को परख कर 'माया' ने अपने संवाददाताओं की टोली को पूरी अमेठी में तैनात कर दिया, ताकि करीब से हिंसा का मुजरा देखा जा सके।

वैसे तो अमेठी में पहले से ही जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन में ऐसे अधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति की गयी थी जो सरकारी पदों पर रहते हुए कांग्रेस और विशेषकर राजीव गांधी के लिए काम करने का रिवार्ड पाते रहे हैं। चुनाव के समय आसपास से विश्वस्त पुलिस जनों को और बुला लिया गया था।

१२ और १४ नवंबर की घटनाओं से उभरी आशंकाओं को देखते हुए अमेठी को केवल पुलिस छावनी की ही शक्ल नहीं दी गयी, बल्कि सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की टोलियां भी अमेठी में सुरक्षा प्रबंध के नाम पर झोंक दी गयीं। २१ नवंबर से ही अमेठी की सड़कों पर पुलिस के जवानों की मोर्चाबंदी शुरू हो गयी थी। जिस तरह से अमेठी में सुरक्षा बल तैनात किया गया, उससे एकबारगी लगा कि अमेठी में बूथ कैप्चरिंग की संभावना नहीं है, लेकिन २२ नवंबर की सुबह यही सुरक्षा बल संदेह के घेरे में आ गया। २२ नवंबर को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे क्रूर उदाहरण अमेठी बनकर उभरा, जब वहां पुलिस की मौजूदगी में बूथ कैप्चरिंग

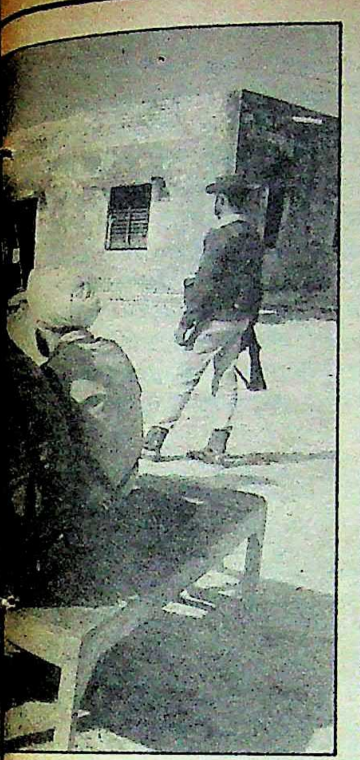

अगर पुलिस प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं था, तो उसने काफिले पर नजर क्यों नहीं रखी? गाड़ियों के दस्ते बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, इसकी जानकारी के बावजूद उनकी नाकेबंदी क्यों नहीं की गयी? अमेठी में घुसने पर प्रेस तक की तलाशी हुई, तो फिर ये दस्ते शस्त्रों के साथ अमेठी में किसकी मदद से घुसे। काफिले के आगे एक-दो दरोगा मोटर साइकिलों पर क्यों थे? ये सवाल अनुत्तरित हैं।

और हिंसा का अभूतपूर्व नाच देखा गया।

२१ नवंबर को अमेठी में सरकारी आतंक और प्रशासनिक गुंडई का दृश्य देखना आम हो गया था। पुलिसवाले खुलेआम जनता दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डरा-धमका रहे थे। दहशत फैलाने के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च भी अमेठी में कराया गया। अमेठी संसदीय क्षेत्र के होटलों में जहां-जहां जनता दल के कार्यकर्ता टिके थे, वहां-वहां पुलिस वालों ने पहुंच कर होटल खाली करके अमेठी से चले जाने तक के लिए कहा। जगदीशपुर के फैजाम होटल में स्थानीय थाने के दरोगा प्रदीप वर्मा ने जनता दल के कार्यकर्ताओं से हाथापाई की और उन्हें होटल खाली करने की धमकी दी। इसी तरह सलोन थाने के दरोगा ने भी जनता दल कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया। संग्रामपुर में तो सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने ही जद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डराया-धमकाया। सड़क पर पुलिस के जवान तैनात थे—जो अमेठी में प्रवेश करने वाली हर गाड़ी की जांच ही नहीं कर रहे थे, बल्कि गाड़ी में सवार की भी तलाशी ले रहे थे। अमेठी से बारह किलोमीटर पहले विशेषगंज के पास जहां से अमेठी की सीमा शुरू होती है—हमारी भी गाड़ी की तलाशी ली गयी—यह बतलाने के बावजूद कि हम प्रेस से हैं। इस व्यवस्था को देखकर लगा था कि अमेठी में हिंसा का खेल हो ही नहीं सकता। लेकिन यह धारणा तब टूट गयी, जब अमेठी में प्रवेश करते ही खबरें मिलने लगीं कि एक के बाद एक बूथ कब्जायी जा रही हैं। जनता दल के पोलिंग एजेंटों को मार कर भगाया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है।

कहने के लिए अमेठी में बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित पुलिस के हजारों जवान तैनात किये गये थे, लेकिन संभवत: इन्हें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी कम दी गयी थी। संजय सिंह के समर्थकों का मुकाबला करने का काम अधिक दिया गया था। अमेठी में चर्चा थी कि कांग्रेसी बाहुबलियों का मुकाबला करने के लिए संजय-सेना सक्रिय है। पर २२ नवंबर को अमेठी में संजय-सेना कहीं नहीं दिखी। दिखी तो बस कांग्रेसी बाहुबलियों की भागती जीपें, वे भी काफिले की शक्ल में।

सूत्रों के अनुसार दस-दस जीपों-कारों की चार टुकड़ियां बनायी गयी थीं, जिनका नेतृत्व अपराधी तत्व कर रहे थे। ये टुकड़ियां हर तरह से सज्जित थीं। इनके तेवर बता रहे थे कि इनके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है जिसने इन्हें कुछ भी करने की छूट और सुविधा दे रखी है। ये ऐसे लोग थे जो तीन दिन पूर्व जनता दल छोड़कर कांग्रेस में आये थे।

अमेठी के संवेदनशील हर पोलिंग बूथ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और होमगार्ड्स की टुकड़ियां तैनात थीं। जो पोलिंग बूथ संवेदनशील नहीं थे, उन पर पुलिस और होमगार्ड्स के पांच-सात जवान तैनात थे। 'माया' टीम जिस भी पोलिंग बूथ पर पहुंची, वहां लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम मतसूची में नहीं हैं। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट खुलेआम पुलिस के सहयोग से फर्जी मतदान कर रहे हैं। अमेठी बाजार में स्थित जूनियर हाईस्कूल की पोलिंग बूथ पर प्रेस गाड़ी पहुंचते ही बहुत से मतदाता दौड़ पड़े और उन्होंने एक स्वर में कहना शुरू किया कि कांग्रेस के लोग अंदर काफी गड़बड़ी कर रहे हैं। मुसलमान और हरिजनों ने शिकायत की कि उनके नाम इस बार मतदाता सूची में हैं ही नहीं। प्रेस टीम से लोग बात कर ही रहे थे कि इसी बीच संजय सिंह एक गाड़ी में आये और ऐसी ही शिकायत लोगों ने उनसे की। 'डरिये मत' का आश्वासन देकर संजय सिंह आगे बढ़ लिये। साईंधाम होटल जब हम पहुंचे, तो वहां पर यूनिटी फारवर्डिंग लखनऊ के इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वे राजमोहन गांधी के लिए १३ गाड़ी लखनऊ से किराये पर लाये थे। जिनमें से तीन डीसीएम टोयटा गाड़ियों (यूजीओ-०६१३८, डीडीएल-३१०३ और एमपी०६-३०८६) को २१ तारीख की रात में दो बजे के लगभग अमेठी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यालय के पास बंदूक-पिस्तौल दिखाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और ड्राइवरों को एक कमरे में बंद कर दिया। रात भर उन्हें डराया-धमकाया और गाड़ियों की चाबी ले ली। इसके बाद उन्हें सुबह १० बजे छोड़ा। छोड़ने के पहले ड्राइवरों की घड़ियां और पैसे तक छीन लिये गये। ड्राइवर पृतपाल सिंह, सतीश कुमार और भूपाल भंडारी घटना का बयान करते सहम रहे थे। इसी दौरान साईंधाम होटल में संजय बेंत के सहारे चलते हुए पहुंचते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस पोलिंग बूथों को लूटने के मूड में है।

छाया: राजेश कुमार

गोरखपुर की ताकत: माखनलाल फोतेदार से बात करते हुए हरिशंकर तिवारी

बातचीत चल ही रही थी कि एक गाड़ी में कुछ लोग भागते आये और संजय सिंह को सूचना दी कि टीकरमाफी में बूथ कैप्चरिंग होनेवाली है। संजय सिंह टीकरमाफी की ओर चल पड़ते हैं। हमारी भी कार पीछे लग जाती है। रास्ते में संजय सिंह की कार रोक कर लोग बताते जा रहे थे कि यहां गड़बड़ी हो रही है, वहां गड़बड़ी हो रही है। मैदान छोड़कर भागते हुए समर्थकों को 'मोर्चा संभाले रहिये' कहकर संजय सिंह आगे बढ़ते रहे। जब हम दिन में ग्यारह बजे टीकरमाफी पहुंचे, तो सड़क के किनारे दस जीपों-कारों का एक लंबा काफिला रुका था। लोग तैश में थे। सैकड़ों की संख्या थी। देखकर ही लग रहा था कि इनके इरादे नेक नहीं हैं। संजय सिंह कार से उतरकर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, तो कुछ वृद्ध उनके पांव छूते हैं। भीड़ बढ़ जाने से मतदाताओं की परेशानी को देखकर पुलिस भीड़ हटाने में लगी थी। काफिले के लोग विरोध प्रकट कर रहे थे कि पहले संजय सिंह और उनके लोगों को यहां से हटाया जाये,

तभी हटेंगे। पुलिस से हाथापाई भी हुई। संजय सिंह समय की नाजुकता को देखकर शांत बने रहे। इसके बाद काफिले के लोग 'अपने बाहुबली नेता' की जय-जयकार करके आगे बढ़ गये। पर जाने के पहले अपने इरादे बता गये कि किसी भी कीमत पर संजय सिंह को जीतने नहीं देना है।

काफिला गुजरने के बाद जब हम वहां से लौटते हैं, तो रास्ते में पता चलता है कि टीकरमाफी से चला काफिला हथकिला पोलिंग बूथ पर अपना आतंक जमा चुका है। हम कच्ची सड़कों से जब हथकिला पहुंचते हैं, तो पोलिंग बूथ पर मतदाता नजर ही नहीं आये। प्रेस की गाड़ी देखकर कुछ लोग पास आते हैं और जानकारी देते हैं कि ११ बजकर ४५ मिनट पर दस गाड़ियों में लोग आये और उन्होंने हवा में कई चक्र गोलियां छोड़ीं। पंक्ति में लगे मतदाताओं को मारा-पीटा और डराया-धमकाया। इसके बाद वे कुछ मतपत्रों को फाड़ गये। इस पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी लक्ष्मीकांत ने रिपोर्ट में दर्ज किया कि दोपहर ११.४५ पर बाहर फायरिंग हुई। शोर-गुल के बाद बूथ कैप्चरिंग हुई जिसमें एकाउंट अस्त-व्यस्त हो गया। कुछ कागजात भी गायब हैं।

यहां पर लोगों ने यह भी बताया कि अभी जो दरोगा आया था, वही पहले भी आया था और ड्यूटी पर तैनात पुलिस और होमगार्ड वालों को कह गया कि एक दल आ रहा है—वह जो करे करने देना, बोलना नहीं। अब वही दरोगा घटना की जानकारी हासिल करने आया है।

कच्ची सड़कों से निकल कर जब हम मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि कटरा फूलपुर में बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ८०-९० की रफ्तार से हम जब पहुंचते हैं, तो वहां दीवार पर फोड़े गये बम के निशान, सूने पड़े बूथ और बूथ से १०० गज दूर खड़े भयभीत मतदाता मिलते हैं। रामसुंदर तिवारी ने बताया कि गाड़ियों का एक काफिला रुका और उसमें से सैकड़ों की संख्या में नौजवान निकले। उन्होंने बूथ पर पहुंचकर बम फेंकने शुरू कर दिये और हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हम लोग डर कर भागने लगे, तो हमको बंदूक के कुंदों से मारा। रामसुंदर ने अपने सूजे हुए हाथ भी दिखाये। चंद्रपाल सिंह भी घायल थे। उन्होंने बताया कि एक बम और लगभग चौदह गोलियां उन लोगों ने चलायीं। ग्रामीण मतदाता यह बता रहे थे कि सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों की एक टोली वहां पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वोट देना है, तो बूथ पर चलो—नहीं देना है, तो यहां से भाग जाओ। देखते-देखते इस बूथ पर केवल सीआरपीएफ के लोग रह गये। इस दृश्य को जब हमारे छायाकार मनमोहन शर्मा ने कैमरे में कैद किया, तो सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने कैमरा छीनने की कोशिश की। हमारे प्रेस टीम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

जो काफिला टीकरमाफी में मिला था, वह जिधर से गुजरा, उसने बूथों पर आतंक मचाया। करौंधी, डेढ़पसारा, बघौरा, इस्माइलपुर आदि बूथों पर उन्होंने वही खेल दुहराया। इस्माइलपुर मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी खुले आम पंजे के पक्ष में मतपत्रों पर मुहर लगाकर मतपेटी में डाल रहे थे।

अमेठी कोठी (संजय सिंह का आवास) का जायजा लेने के लिए जब हम २.४० पर पहुंचे, तो कोठी के स्वागत कक्ष में संजय गांधी के चित्र के नीचे बैठा एक व्यक्ति टेलीफोन पर कहां-कहां बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस वालों ने की है, इसकी जानकारी एकत्र कर रहा था। इस बीच एक युवक दौड़कर आता है और बताता है कि बघौरा मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग हो गयी है। बूथ को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलायी जा रही हैं। उस युवक को लेकर हम बघौरा की ओर जाना चाहते थे कि उस भयभीत युवक ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और बोला कि वे लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे जान से मार डालेंगे। उस युवक से रास्ता पूछ कर जब हम बघौरा पहुंचे, तो देखा सब कुछ अस्त-व्यस्त है और आतंक छाया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काफिला मुंशीगंज बाजार की ओर गया है। मुंशीगंज थाने से बघौरा की दूरी एक किलोमीटर है—पर बघौरा में चली गोलियों की खबर थाने तक शायद नहीं पहुंची और पहुंची भी, तो वहां सैकड़ों की संख्या में खड़े पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने उसकी परवाह नहीं की। हम बघौरा से मुंशीगंज बाजार की ओर बढ़ने ही वाले थे कि सतीश शर्मा जिप्सी चलाते हुए और पीछे सुरक्षाकर्मियों से भरी जिप्सी के साथ गुजरे। बघौरा बूथ पर एक मिनट के लिए रुके और 'सब ठीक रहा' पूछ करके आगे बढ़ लिये। ९०-१०० की रफ्तार से सतीश शर्मा की जिप्सी भागी जा रही थी और उनके पीछे हम लगे हुए थे। गौरीगंज डाक बंगले में उनकी गाड़ी रुकते ही हम उन्हें बात करने के लिए पोर्टिको में ही रोक लेते हैं। हमने उनसे कहा कि जीपों के काफिले आतंक मचाये हुए हैं, तो उन्होंने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज पीसफुल। यह संजय सिंह का स्टंट है।" गौरीगंज निरीक्षण गृह में तीन बजे बात करते समय सतीश शर्मा ने यह भी कहा कि संजय सिंह हार नहीं रहे हैं, वे आउट भी हो रहे हैं। आउट होने पर उन्होंने कई बार बल दिया। इस बीच एक जीप आकर रुकती है। उसमें से कुरता-पाजामा-जैकेट पहने और कंधे पर शाल डाले एक लंबा तगड़ा व्यक्ति उतरता है और सतीश शर्मा से 'खास बात' कहकर अंदर की ओर बढ़ जाता है। सतीश शर्मा हमें तुरंत नमस्कार करके उस व्यक्ति के पीछे हो लेते हैं और एक कमरे में बंद हो जाते हैं।

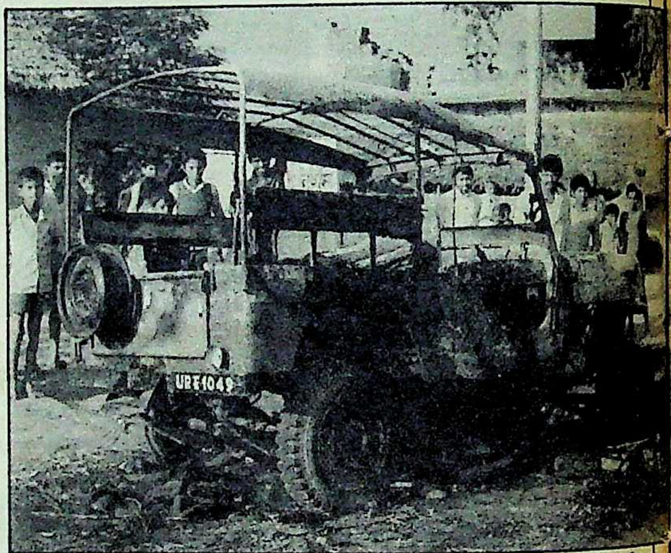

संजय सिंह पर हमले के बाद इंका की क्षतिग्रस्त जीप

छाया : मनमोहन शर्मा

३.४५ पर हम मुंशीगंज बाजार में पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि भुसियावां चौराहे पर संजय सिंह को गोली मार दी गयी। भुसियावां हम पहुंचते हैं, तो खबर मिली कि संजय सिंह को लेकर लोग सुल्तानपुर गये। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भुसियावां चौराहे पर साढ़े तीन बजे कांग्रेसी काफिले और संजय सिंह की गाड़ी आमने-सामने आ जाती है। काफिले के लोग जिसमें दस-बारह जीपें तथा कारें थीं, चारों तरफ से संजय सिंह को घेर लेते हैं और फिर एक-एक करके दस-बारह बम फोड़े जाते हैं। चारों तरफ धुआं-ही-धुआं हो जाता है। इसी दौरान संजय सिंह अपनी गाड़ी से उतरते हैं कि उनके पेट में गोली मार दी जाती है। गोलियां चलती रहती हैं, जिनसे संजय सिंह का अंगरक्षक और ड्राइवर भी घायल हो जाता है। एक युवक भी घायल होता है। काफिले के बारे में जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शी देते हैं, उसकी शक्ल टीकरमाफी में मिले काफिले से मिलती-जुलती है। संभवतः टीकरमाफी में उस दल के लोग शाम को जिस खेल को खतम करने की बात आपस में कर रहे थे—वह यही खेल था।

८०-९० की रफ्तार से हम सुल्तानपुर भागते हैं। वहां पहुंचने पर पता चला कि उन्हें लखनऊ ले जाया गया है। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में घायल युवक से मिले, तो पता चला कि यह वही युवक था, जिसने अमेठी किले में हमारी गाड़ी में बैठने से इनकार किया था। घायल ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि जैसे ही हम लोग अमेठी किले से बघौरा के लिए गये, वैसे ही संजय सिंह किले में आये, तो उन्हें घटनाओं के बारे में बताया गया। उन्हें पता चला

कि कांग्रेसी काफिला मुंशीगंज रोड से भुसियावां की ओर गया है। उस दल का पीछा करने वे निकले ही थे कि भुसियावां चौराहे पर आमना-सामना हो गया। फिर बम के धमाके हुए और तड़ातड़ गोलियां चलने लगीं। घटना के संबंध में बात करने के लिए जब हम सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचते हैं, तो पता चला कि साहब नहीं हैं और संजय सिंह को गोली लगने की जानकारी नहीं है। जोर देने पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने मुंशीगंज थाने फोन किया, तो उसे बताया गया कि शायद अफवाह है कि संजय सिंह को गोली लगी है। शाम सात बजे जब हम अमेठी पहुंचते हैं, तो बाजारों की चहल-पहल रुक गयी थी—लोग भयभीत और उत्तेजित थे। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि 'कुंवर साहब' (यानी संजय सिंह) की हालत कैसी है। दो जीपें फूंकी जा चुकी थीं। माहौल में तनाव था।

यह तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि संजय सिंह पर हुआ हमला सुनियोजित था, लेकिन २२ नवंबर को चुनाव के समय जो कुछ हुआ, वह सुनियोजित था। १६ तारीख से २१ तारीख के बीच सतीश शर्मा की गतिविधियां गौरतलब हैं। १६ नवंबर को गौरीगंज निरीक्षण गृह में जब कुछ लोग उनसे शिकायत करते हैं कि उनके हथियार पुलिस ने जमा करवा लिये हैं, तो सतीश शर्मा तुरंत सुल्तानपुर और रायबरेली के पुलिस अधीक्षकों को आदेश देते हैं कि जमा कराये गये हथियार वापस कर दिये जायें।

२१ नवंबर को गौरीगंज निरीक्षण-गृह के एक कमरे में बैठक हुई थी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बूथ कैप्चरिंग की पूरी योजना बनायी गयी थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से राजीव को जिताने के लिए कमर कस चुका था। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन व्यक्तियों की जेब पर पीले और लाल रंग के तीन-तीन बटन लगे हों, वे जो भी करें, उन्हों रोका न जाये। इस बात की जानकारी कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को भी दे दी गयी थी।

अगर पुलिस प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं था, तो उसने काफिले पर नजर क्यों नहीं रखी? गाड़ियों के दस्ते बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, इसकी जानकारी के बावजूद उनकी नाकेबंदी क्यों नहीं की गयी? अमेठी में घुसने पर प्रेस तक की तलाशी हुई, तो फिर ये दस्ते शस्त्रों के साथ अमेठी में किसकी मदद से घुसे? काफिले के आगे एक-दो दरोगा मोटर साइकिलों पर क्यों थे? ये ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं।

बूथ कैप्चरिंग का मतलब तो अब तक यह होता था कि बूथ कैप्चर करनेवाले अपने ही हाथों से मतपत्रों पर मुहर लगाकर मतपेटी में डाल देते थे। पर इस बार अमेठी में एक नयी शैली का दर्शन हुआ। काफिले रुकते थे और आतंक मचाकर चले जाते थे। मतपत्रों पर मुहर लगाकर डालने का काम पोलिंग एजेंट और अधिकारी आराम से करते थे। क्योंकि उन्हें रोकने-टोकनेवाला कोई रह ही नहीं जाता था। सूत्रों के अनुसार जिन बूथों पर राजीव गांधी को अत्यधिक मत मिलने की उम्मीद थी, उन्हें संवेदनशील घोषित करके भरपूर पुलिस बीएसएफ आदि लगा दी गयी थी और जहां संजय सिंह का समर्थन ज्यादा था, वहां नाम मात्र की सुरक्षा व्यवस्था थी। कम सुरक्षावाले बूथों पर जब मतदाताओं की भीड़ लग जाती थी, तो मत दस्यु दस्ता नमूदार होता था और फिल्मी अंदाज में ठांय-ठांय गोलियां चलाकर आतंक मचा देता था। परिणामस्वरूप मतदाता भाग जाते थे और मतदान केंद्र सूने हो जाते थे।

अमेठी में किस कदर बूथ कैप्चरिंग हुई, उसका उदाहरण तो यही है कि निर्वाचन आयोग को ६७ बूथों पर पुनः मतदान करवाना पड़ा। सुल्तानपुर के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को धांधली करवाने का दोषी पाया गया। २६ नवंबर को हुआ पुनः मतदान भी पाक-साफ नहीं रहा। हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई, तो धांधली का रूप एक बार फिर उभरा। बूथ पर पड़े मत से अधिक संख्या में मतपत्र-मतपेटी से निकले थे। जीत सुनिश्चित होते हुए भी राजीव गांधी ने हिंसा और धांधली का सहारा क्यों लिया, यह बात समझ में नहीं आती। यह उनके आत्मविश्वास खो देने का द्योतक था या वफादारों द्वारा अतिवफादारी दिखाने की हिमाकत थी?

—अमेठी से लौटकर दिनेश दीनू

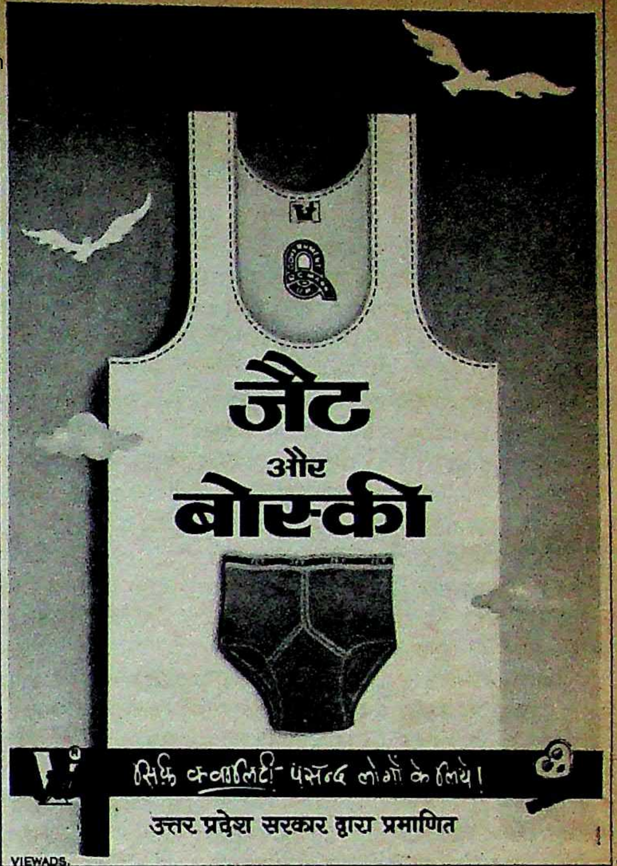
जैट
और
बोस्की
सिर्फ क्वालिटी-पसन्द लोगों के लिये।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित
VIEWADS.

Look Lovelier
this year
next year
every year
Boski®
BRA & PANTIES
VIRA ADS

VENUS HOSIERY
RAJBI ROAD, KANPUR
PHONES: 67491, 67492

Dealers enquiries are solicited in unrepresented areas.

चुनाव परिणामों का गणित

अधिकांश भविष्यवाणियां मोटे तौर पर सही होते हुए गलत साबित हुईं। सही भविष्यवाणी कांग्रेस अथवा उसकी सहयोगी पार्टियों की सीट को लेकर थी। किंतु हरेक भविष्यवाणी के कुछ भाग गलत साबित हुए। किसी ने भी आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम के सफाये अथवा राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, बिहार में कांग्रेस-इ के सफाये की भविष्यवाणी नहीं की थी। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर पाया था कि कांग्रेस को गुजरात में ३, उड़ीसा में २ और बिहार में मात्र ४ सीटें मिलेंगी। इस प्रकार कोई भी भविष्यवक्ता यह नहीं सोच सका था कि तमिलनाडु में द्रमुक को एक भी सीट नहीं मिलेगी अथवा कर्नाटक में विपक्ष को केवल एक सीट मिलेगी।

किंतु चुनाव में ऐसा ही होता है। खासकर जब मतदाताओं की तादाद लगभग ५० करोड़ हो और उनमें से आधे से ज्यादा मतदान करें। इसके अलावा ये मतदाता देश के विभिन्न राज्यों के हैं और जिनका अलग-अलग इतिहास और राजनीतिक समीकरण है। और-तो-और स्वयं राजनीतिक दल भी कुछ चुनाव परिणामों को लेकर हतप्रभ हैं। यद्यपि उनका सीधा संबंध-संपर्क लाखों मतदाताओं से था।

अनेक चीजें ऐसी साबित हुईं जो किसी पूर्वानुमान के बाहर थीं। शासक दल के वोटों के प्रतिशत में जो जबरदस्त गिरावट आयी है, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। गुजरात में कांग्रेस को १९८४ में जितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, इस बार उसमें १६ प्रतिशत की गिरावट आयी। राज्य में पार्टी को १९८४ में ५३.२४ प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार उसे लगभग ३७ प्रतिशत वोट मिले। यही बात लगभग समूचे हिंदी भाषी क्षेत्र में देखने को मिली। उप्र, राजस्थान और बिहार में १९८४ की तुलना में १५ से २० प्रतिशत वोट कांग्रेस को कम मिले।

हरियाणा और दिल्ली बहरहाल इसके अपवाद रहे। इन दो राज्यों में कांग्रेस के वोटों की क्षति काफी कम है। इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को १० में से ४ और दिल्ली में ७ में से २ सीटें मिलीं। जबकि उप्र में ८५ में से १५ और बिहार में ५४ में से ४ सीटें मिलीं।

कर्नाटक, केरल, आंध्र व तमिलनाडु में कांग्रेस की किस्मत ने एक जैसा रंग नहीं दिखाया। आंध्र प्रदेश में शासक दल तेलुगूदेशम के वोटों में ३ प्रतिशत की गिरावट आयी और इससे थोड़ा अधिक कांग्रेस के वोटों में वृद्धि हुई। मजेदार बात तो यह है कि तमिलनाडु में शासक दल द्रमुक के वोटों के प्रतिशत में वृद्धि हुई। यह वृद्धि १९८९ के जनवरी में संपन्न विधानसभा चुनावों की तुलना में हुई है। द्रमुक का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनावों में ३३ प्रतिशत था। उस समय तिकोनी प्रतिद्वंद्विता होने के कारण द्रमुक विजयी हुआ था। इस बार अन्नाद्रमुक कांग्रेस का गठजोड़ होने से द्रमुक के मत प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद उसकी पराजय हुई।

केरल में वामपंथी मोर्चा व कांग्रेस नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चा दोनों के वोट प्रतिशत में १९८४ की तुलना में वृद्धि हुई है। यद्यपि लोकतांत्रिक मोर्चे का प्रतिशत अधिक बढ़ा है। इसके अलावा वोटों का थोड़ा विभाजन हुआ, जिसमें भाजपा उम्मीदवारों का योगदान था। इस आम धारणा के बावजूद कि कांग्रेस के कर्नाटक के वोट प्रतिशत में बहुत वृद्धि हुई है, सचाई यह है कि उसमें कोई वृद्धि ही नहीं हुई। किंतु कांग्रेस की सीट में वृद्धि अवश्य हुई है। इसका मुख्य कारण तिकोनी प्रतिद्वंद्विता रही, जिसमें जनता दल और देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी आपस में कोई समझौता नहीं कर पायी।

सवाल यह है कि क्या हर राज्य में स्थानीय शासक दल के खिलाफ नकारात्मक वोट पड़े? पश्चिम बंगाल के प्रश्न पर ऐसा कतई नहीं हुआ, क्योंकि सीट और वोटों के प्रतिशत में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा को वृद्धि का लाभ प्राप्त हुआ। १९८४ में राज्य में कांग्रेस को जहां १६ लोकसभा सीटें मिली थीं, इस बार केवल ४ ही हाथ आयी हैं। एक सीट गोरखा नेशनल फ्रंट उम्मीदवार को मिली और जिन ४१ सीटों के लिए चुनाव हुए, उनमें से शेष ३६ में माकपा, भाकपा और अन्य वामपंथी दलों की विजय हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में जब हम देखते हैं कि स्थानीय शासक दल के वोट में वृद्धि हुई या कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं हुई, तो इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है कि मतदान राज्य में सत्तारूढ़ दल विरोधी था। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन के पूर्व हेगड़े व बाद में बोम्मई के नेतृत्व में जनता सरकार सत्तारूढ़ थी।

उत्तर-पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्रों में कांग्रेस को दस में से दसों सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र एक और ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस की १९८४ की तुलना में वोटों और सीटों में थोड़ी सी गिरावट आयी है। राज्य में शहरी इलाकों और तीन-चार ग्रामीण इलाकों में भाजपा-शिवसेना गठजोड़ को सीटें मिली हैं और वहां कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट आयी है। महाराष्ट्र में शेष क्षेत्र में गिरावट या तो नाममात्र की है अथवा उसका वोट प्रतिशत सुरक्षित है। इस प्रकार महाराष्ट्र के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय सरकार के खिलाफ मतदाता के रुख में कोई भारी परिवर्तन हुआ है।

इसके विपरीत देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस विरोधी मतों के प्रतिशत में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है कि यह कम-से-कम शासक दल के खिलाफ एक जनादेश है। अब सवाल यह है कि यह स्थानीय सरकार के खिलाफ है अथवा केंद्र सरकार के खिलाफ? कम-से-कम इन राज्यों में इन दोनों सरकारों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि यह जनादेश कितना स्थानीय शासन के विरुद्ध है और कितना राजीव सरकार के खिलाफ इसकी कोई मात्रा तय नहीं की जा सकती। किंतु यह बात अवश्य स्पष्ट है कि जब चुनाव केंद्र सरकार (लोकसभा) के लिए है, तो केंद्र सरकार (राजीव सरकार) के खिलाफ यदि मतदाताओं का रवैया अत्यधिक उग्र न होता, तो मतों के प्रतिशत में इतनी भारी गिरावट न आती।

दो अन्य अहम मुद्दे पुरानी वोट शैली से संबंधित हैं। अनुसूचित जाति के जो वोट परंपरा से कांग्रेस को जाते थे, उनमें बहुत परिवर्तन आया है। कुछ राज्यों—खासकर उप्र व पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को अनुसूचित जाति के काफी वोट मिले हैं। इस वर्ग के वोट का एक अच्छा-खासा भाग अन्य विपक्षी दलों को मिला है। लगता है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति के ५० से ६० प्रतिशत वोट से अधिक नहीं ले पायी।

मुस्लिम मतदाताओं के रवैये में क्षेत्रवार बदलाव आया है। हिंदीभाषी राज्यों और गुजरात में आमतौर पर भारी तादाद में मुस्लिम वोट कांग्रेस के खिलाफ गये हैं। इसमें भी बिहार में कांग्रेस के विरोध में जितना मुस्लिम झुकाव आया, उतना उप्र में नहीं। पश्चिम बंगाल में स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। दक्षिणी राज्यों में मुस्लिम मतदाता सामान्यतः कांग्रेस के साथ रहे।

इस समूचे राजनीतिक परिदृश्य से यह बात साफ होती है कि जाति-धर्म अथवा प्रांतीयता मतदाता के मतदान-निर्णय में कोई अहम भूमिका नहीं निभा पायी। यह ठीक है कि राम जन्मभूमि के प्रश्न पर जो तनाव पैदा हुआ, उसका कुछ प्रभाव हिंदी भाषी राज्यों में अवश्य पड़ा। किंतु कुल मिलाकर इसकी कोई निर्णायक भूमिका नजर नहीं आती। इसी से यह भी उजागर है कि हिंदू कार्ड जितना राजनीतिक दलों के दिलोदिमाग में रहा, उतना मतदाताओं में नहीं। इसलिए नयी सरकार सीटों के गणित से कब तक बरकरार रहेगी, यह तो कहना कठिन है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने ज्यादातर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर मतदान किया है और यही भारतीय लोकतंत्र का एक सुदृढ़ स्तंभ सिद्ध हुआ है।

—कुमारेश चक्रवर्ती

हज़ारों में होता है कोई एक पुरुष, जिसकी नज़र में होती है शान और बेहतरीन फ़ैब्रिक की पहचान.

फ़ैब्रिक, जिसमें हो बेहतरीन फ़ॉल और ड्रेप.

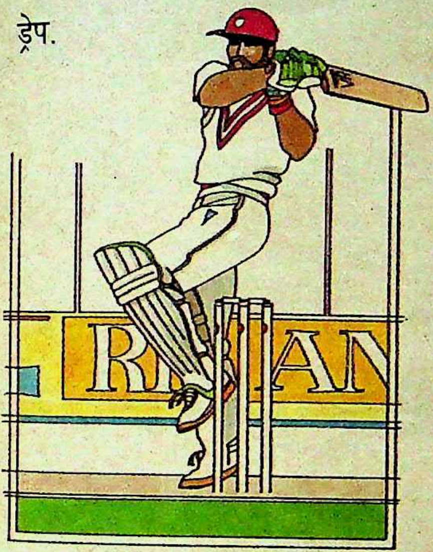

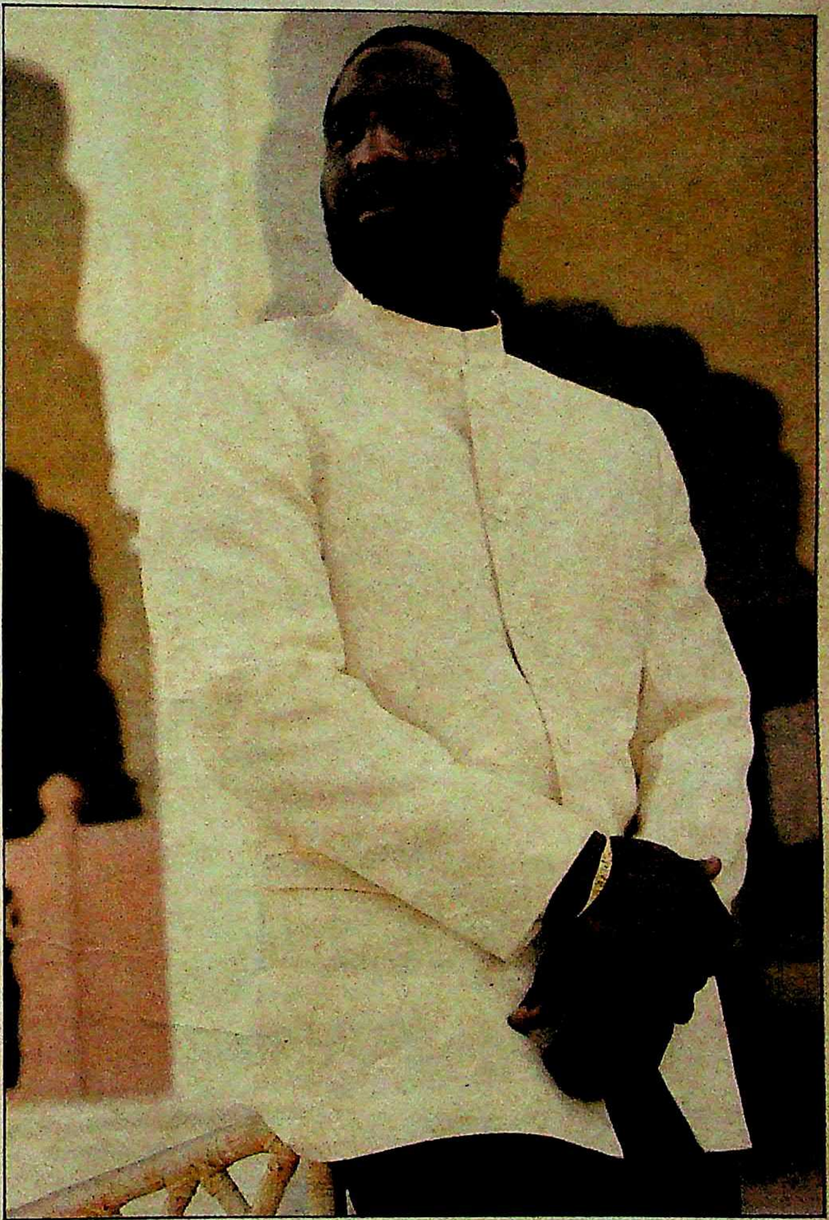

और ऐसे पुरुष सिर्फ़ विमल की ख़ास वर्स्टेड वूलन रेंज की ही माँग करते हैं. ऐसा फ़ैब्रिक जिसके फ़ॉल और ड्रेप की खूबियां फ़ाइबर से शुरू होती हैं. बहुत ही बारीकी एवं ध्यान से बुना हुआ बेहतरीन ऊन और कृत्रिम फ़ाइबर का मिश्रण.

और इसका परिणाम है एक ख़ास फ़ैब्रिक. जैसा कि इसको पहनने वाला. जो हमेशा इस खास फ़ैब्रिक की ही माँग करता है.

विमल के वर्स्टेड वूलन्स

VIMAL
WORSTED WOOLLEN
& POLYRICH SUITINGS

वर्स्टेड वूलन एवं पॉलिरिच सूटिंग्स

Mudra:A:RIL:4994:A:Hin.

उत्तर प्रदेश

मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री कैसे बने ?

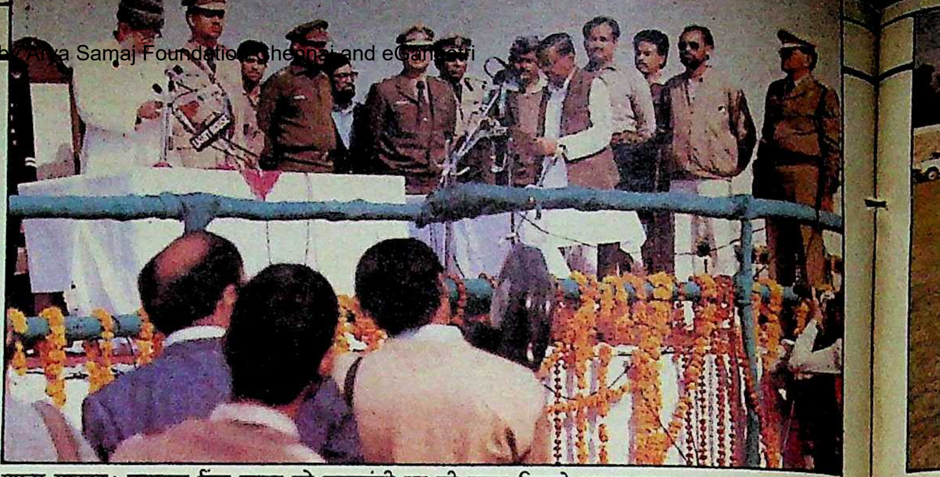

सपना साकार: मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए राज्यपाल

२६ नवंबर की दोपहर तक सब ठीक था। जनता दल बहुमत की ओर था और नेता पद के लिए नाम एक ही था— मुलायम सिंह यादव। लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी कि जिसने 'क्रांति रथ' पर चढ़ नारायण दत्त तिवारी की 'झटके की राजनीति' को ध्वस्त किया हो, उसे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पर इसी दिन प्रदेश के एक बड़े अखबार ने 'मध्यान्ह' संस्करण निकालकर अजीत सिंह को भी मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल कर दिया। २८ नवंबर के बाद घटकवाद की यह फुसफुसाहट बहुत कुछ साफ सुनायी पड़ने लगी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जद के चुनाव प्रभारी मधुकर दिघे को बयान देना पड़ा कि अजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को इस होड़ में शामिल करके उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही है। मुलायम सिंह यादव के कट्टर समर्थक विधायक बेनी प्रसाद वर्मा ने भी बयान देकर अजीत को 'राष्ट्रीय नेता' करार देते हुए उनके राष्ट्रीय राजनीति में शिखर पर पहुंचने की कामना के साथ उन्हें 'रेस' से दूर ही रखा।

खेल की शुरुआत: २६ नवंबर को अजीत समर्थक जद सांसद सत्यप्रकाश मालवीय ने अपना बोरिया-बिस्तर लखनऊ में ही डाल दिया और इस अभियान में अजीत को खींचने वाले जद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और हारे हुए विधायक राजेंद्र सिंह को हाथ में हाथ डाल इस खेल का औपचारिक श्रीगणेश कर दिया। समर्थक विधायकों की सूची बनी, तो उनका उत्साह बढ़ा। सूची के खेल ने मुलायम सिंह को चेताया और विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास से सूची के साथ हस्ताक्षर अभियान भी शुरू हुआ। २६ की रात तक १०२ विधायक मुलायम सिंह को अपने हस्ताक्षर दे चुके थे।

राजेंद्र सिंह के माल एवेन्यू स्थित घर पर भोज की राजनीति भी शुरू हो चुकी थी। राजेंद्र सिंह भी हस्ताक्षर अभियान में जुटे, तो दो दिसंबर तक उन्हें ७६ विधायक ही नजर आये। राजेंद्र सिंह, विरोधी दल के नेता सतपाल यादव और सत्यप्रकाश मालवीय की कोशिशें लोकदल-अ विधायकों तक ज्यादा सीमित होती दिख रही थीं, जबकि मुलायम सिंह यादव समर्थक अपने लोकदल-ब (६५) के अतिरिक्त जनमोर्चा से जुड़े २३, जनता पार्टी के ११ और संजय मंच के तीन विधायकों से हस्ताक्षर ले चुके थे। लोकदल-अ के खाते से बने छह अन्य विधायक मुलायम सिंह को अपने सहयोग का वचन दे चुके थे। यह बात दूसरी थी कि दो दिसंबर की देर रात सत्यप्रकाश मालवीय इन विधायकों से अजीत के समर्थन में अपनी सूची में हस्ताक्षर कराने में सफल हो गये थे। पर यही विधायक डेढ़ बजे रात मुलायम सिंह के खेमें में लौटकर उनसे अपने पुराने वायदे को दोहरा रहे थें।

दो दिसंबर की दोपहर राजेंद्र सिंह के घर पर हुई भोज-राजनीति का केंद्र स्व० चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी भी रहीं। अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाओ अभियान के जनक राजेंद्र सिंह के पास विधायकों के हस्ताक्षरों की जब कमी पड़ी, तो उन्होंने विधायकों के सामने यह तर्क रखा कि फैसला सर्वसम्मत से कराने की कोशिश की जाये। यानी केंद्र सीधे-सीधे अपनी इच्छा बताकर अजीत को उप्र का मुख्यमंत्री बना दे। तर्क तीन थे। एक देवीलाल के उपप्रधानमंत्री बनने के बाद अब हिस्सा लोकदल-अ को मिलना चाहिए। जनमोर्चा के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हो गये। लोकदल-ब के उपप्रधानमंत्री। इसलिए लोकदल-अ को सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। दूसरा, ओमप्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने से भी लोकदल-ब की दावेदारी कमजोर हुई। तीसरा, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा, जहां जद को संसदीय चुनाव में बड़ी सफलताएं मिली हैं, वहां विधानसभा चुनावों में संभावित सफलता से वे लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उन जगहों पर 'अ' का आधार कमजोर है। जद के केंद्रीय पर्यवेक्षक मधु दंडवते, चिमनभाई पटेल, राजेंद्र सिंह के इस तर्क से सहमत भी होते नजर आ रहे थे। उन्होंने

नया मंत्रिमंडल

घटकवाद को दबाने का प्रयास

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए विपक्ष ने ५ दिसंबर को दोपहर साढ़े बारह बजे लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में १३ मंत्रियों के साथ अपनी सरकार बना ली। घटकवाद से निपटकर ऊहापोह की स्थिति से उबरते हुए मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका था, जब प्रदेश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की जगह खेल मैदान में हुआ। हंगामे की स्थिति यह थी कि राष्ट्रीय गीत की धुन, धमा-चौकड़ी में गुम हो गयी। वहां मौजूद प्रदेश के खारिज हुए मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव समेत निवर्तमान कांग्रेसी मंत्री इस दृश्य को देखकर मंद-मंद मुस्काते रहे। राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ के लिए भी यह एक नया तजुर्बा था।

मुलायम सिंह यादव ने अपने मंत्रिमंडल में जिन १३ विधायकों को मंत्री का पद दिया उनमें ६—रेवती रमण सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, सच्चिदानंद वाजपेयी, मुख्तार अनीस, श्रीमती सुखदा मिश्रा और अवधेश प्रसाद पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इनमें सच्चिदानंद वाजपेयी १९८० में, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रीमती सुखदा मिश्रा १९८५ में नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्यमंत्री का सुख भोग चुके हैं। जबकि रेवती रमण सिंह, मुख्तार अनीस, बेनी प्रसाद वर्मा, अवधेश प्रसाद जनता शासन काल में राज्यमंत्री रहे थे। ७ लोग पहली बार मंत्री बने हैं, इनमें रामशरण दास, दिवाकर विक्रम सिंह, मो० आजम खां, विक्रमादित्य

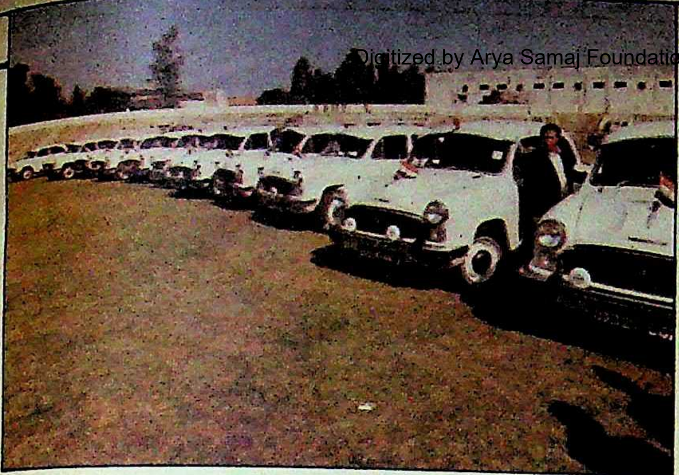

सत्ता के नये सवारों का इंतजार : नये मंत्रियों के लिए तैयार उप्र सरकार की कारें

फार्मूला निकाला कि अजीत मुख्यमंत्री हो जायें और मुलायम उपमुख्यमंत्री। पर मुलायम राजी न हुए। उन्होंने कहा, "मेरे साथ बहुमत है—विधायक भी।" देर रात उन्होंने तीनों पर्यवेक्षकों के सामने राज्य अतिथि गृह में १०-१० के गुटों में ९७ विधायकों को सामने भी कर दिया।

अजीत को धोखा : तीन दिसंबर की सुबह अजीत सिंह भी लखनऊ आ गये। उनके समर्थक विधायक उन्हें लेने पहुंचे। 'जिंदाबाद' के नारों के बीच उन्हें भी लगा कि उनके साथ बहुमत है। पर जब नौ बजे सुबह उन्होंने राजेंद्र सिंह से लिस्ट मांगी, तो उसमें ८९ विधायकों के हस्ताक्षर थे। लिस्ट में उसी दिन सुबह कराये गये जनता पार्टी के चार विधायकों के हस्ताक्षर भी थे। राजभवन

पांडेय, बर्फिया लाल, मुहम्मद असलम खां तथा शतरुद्र प्रकाश हैं। मुलायम सिंह ने अपने इस काबीना स्तर के कुनबे में चारों घटकों को पूरी तरह संतुलित करने का प्रयास किया है। इस पहले दौर में लोकदल-अ के ३, जनता पार्टी के २ जनमोर्चा के २ विधायकों सहित मुलायम सिंह ने अपने घटक लोकदल-ब से संबद्ध ६ को मंत्री बनाया है। इस मंत्रिमंडल में झांसी, बरेली, आगरा और कुमायूं मंडल का प्रतिनिधित्व नहीं है। इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, गढ़वाल और मुरादाबाद मंडल से एक-एक तथा मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद और बनारस मंडलों से दो-दो विधायकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। इस मंत्रिमंडल में एक विशेष बात यह रही कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी जाति के एक भी विधायक को अभी मंत्री बनने का सुख प्रदान नहीं किया। ऐसा करके वे जातिवाद के आरोप से बचना चाहते हैं।

जनता शासन काल में २३ जून १९७७ को राम नरेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने अपने साथ केवल ४ विधायकों को मंत्री बनाया था। दूसरे दौर में ४ जुलाई १९७७ को यादव ने १२ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर काबीना स्तर के मंत्रियों की संख्या १६ कर ली थी। जनता शासन के दूसरे मुख्यमंत्री बनारसी दास ने भी पहले दौर में २८ फरवरी १९७९ को ६ विधायकों को मंत्री बनाकर अपना मंत्रिमंडल गठित किया था, जबकि दूसरे दौर में ६ मार्च १९७९ को उन्होंने रामनरेश यादव और नारायण सिंह को उपमुख्यमंत्री बनाते हुए २० अन्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। २२ नवंबर '७९ को ही एक अन्य विधायक लक्ष्मण सिंह को भी साथ लेकर उन्होंने काबीना स्तर के मंत्रियों की संख्या २९ तक बढ़ा ली थी।

विपक्ष की दूसरी बार बनी इस सरकार में मुलायम सिंह यादव ने पिछली बार की विपक्षी सरकार के मंत्रिमंडल की अपेक्षा पहले दौर में ज्यादा मंत्री बनाये हैं। इन १३ मंत्रियों की शपथ होने के बाद भी घटकवाद का बुखार उतरता नहीं नजर आता। कदाचित इसीलिए मुलायम सिंह ने इस बीमारी की नब्ज पकड़ रखी है। स्थिति देखकर वे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ को राज्यमंत्री और उपमंत्री बनाकर शांत करेंगे और जो ज्यादा मुखर होता नजर आयेगा उसे कैबिनेट में बुला लेंगे। शपथ ग्रहण के समय और बाद की भी प्रतिक्रियाएं यह जताती हैं कि मुलायम सिंह यादव को अभी कई बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ सकता है।

कभी अपने दोस्तों के हाथ में हाथ डालकर गालीगलौज की भाषा में बतियाने-टहलने और पत्रकारों से लपक कर मिलने वाले उन विधायकों के रुख रोबीले हो चुके थे, जब वे मंत्री की शपथ लेने के बाद लालबत्ती लगी कार में बैठने की हैसियत पा गये थे। इनमें ७ वे विधायक थे जो पहली बार मंत्री बनने के स्वप्न की हकीकत जान सके। शपथ ग्रहण समारोह से लौटते ही इन मंत्रियों ने सचिवालय स्थित कमरों को कब्जे में ले लिया। ऐसे लोगों में पहले मोहम्मद असलम खां थे, जिन्होंने पौने दो बजे ही सचिवालय पहुंचकर सबसे पहले पूर्व सिंचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी के कमरे को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में कुछ देर कुरसी पर भी बैठकर मजा लिया।

मुलायम सिंह यादव के इस १३ सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी एक भी ऐसा मंत्री नहीं है, जो संसदीय कार्य में माहिर हो। यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पाकर आम जनता में नयी आशाएं बलवती हुई हैं। समाजवाद के चिंतक, आम जनता से जुड़े मुलायम सिंह का हर कार्य एक नयी पहल होगा। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने 'माया' से कहा, "हमने आम जनता की तरह कल तक वह सब भोगा है जो कांग्रेसी शासन में हुआ। हमें अब मौका मिला है, जाहिर है हमारा पहला प्रयास जनहित का ही होगा। सभी घटकों का हमें सहयोग मिला है। १९७७ का घटकवाद हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार अच्छा कार्य करेगी और स्थायित्व प्राप्त करेगी।"

—सुरेश द्विवेदी

कालोनी स्थित घर में अजीत सिह ने सत्यप्रकाश मालवीय से यह भी पूछा "सचमुच ये लोग मुझे वोट देंगे?" अजीत समर्थक डा० यशवीर और राजेंद्र सिह ने फौरन विश्वास दिलाया कि जनमोर्चा और जनता पार्टी गुटवाले भी आपके साथ हैं। इस हिसाब से अजीत के पास १२५ विधायक दिखते थे। पर उन सबके हस्ताक्षर न होने से अजीत परेशान थे।

नतीजतन, अजीत ने अन्य दलों के विधायकों से बातचीत करनी शुरू की। जनता पार्टी के ओमप्रकाश श्रीवास्तव सहमत थे। जनता दल के सच्चिदानंद वाजपेयी भी तैयार थे। जनमोर्चा के सांसद आरिफ मोहम्मद खां भी। पर किसी ने अजीत को लिखकर नहीं दिया। अजीत को आरिफ ने भी समर्थन दिलाने का वायदा किया। यह माना गया कि यह समर्थन 'वीपी' की ओर से है।

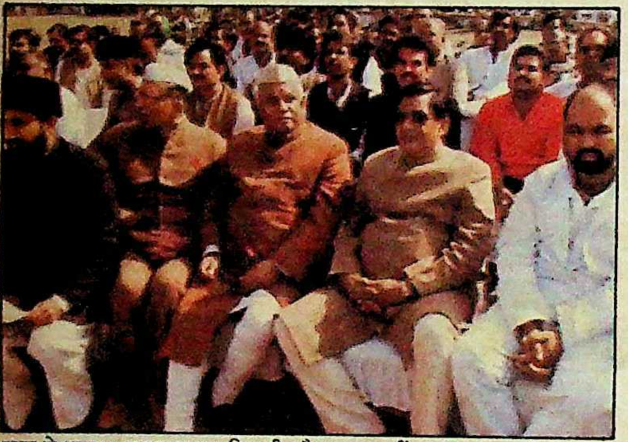

सत्ता से अलग : नारायण दत्त तिवारी और बलराम सिंह शपथ ग्रहण के समय

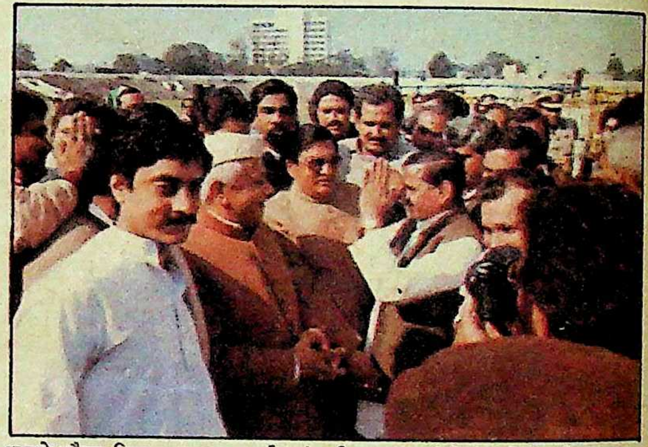

आपने मौका दिया, धन्यवाद : पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री आमने-सामने

फार्मूले की खोज : इस बीच 'फार्मूला' खोजने के लिए मुलायम-अजीत को सुबह ९ बजे और दोपहर ढाई बजे पर्यवेक्षकों की बैठक में शामिल होना पड़ा। अजीत सिंह, मुलायम को उपमुख्यमंत्री बनाने पर सहमत थे और मुलायम किसी भी अजीत समर्थक को उपमुख्यमंत्री। केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरे फार्मूले से सहमत थे। बात न बनती देख मधु दंडवते तो एक तरह से इन दोनों नेताओं को कमरे में छोड़ बाहर आ गये और 'माया' से बोले, "एक बार फिर बैलेट से चुनाव हो जाने दीजिए।"

दूसरी तरफ विधायक दल के नेता के चुनाव का स्थल तिलक हाल का हाल बुरा था। यहां सब कुछ अव्यवस्थित था। लग रहा था कि 'जनता राज' आ गया है। 'पास' और पुलिस के बंधन टूट चुके थे। तिलक हाल में विधायक कम समर्थक ज्यादा थे। तिलक हाल के आसपास गैलरी और छत पर समर्थक थे। कोई विधायक आता, तो उसके समर्थक, 'प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, अजीत या मुलायम जैसा हो' का नारा लगाते। सचिवालय के चारों तरफ बसें, कारें और गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। सचिवालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का कहना था, इतनी अव्यवस्था तो १९७७ में भी नहीं थी। डर के मारे महिला विधायक तो बैठक में आने से कतरा रही थीं। स्वयं आरिफ मोहम्मद खां अपनी विधायक पत्नी रेशमा आरिफ को 'बैक डोर' से अंदर ले गये।

> जैसे ही छह बजकर
> २० मिनट पर निर्णय हुआ 'मुलायम सिंह
> जिंदाबाद' के गगनभेदी नारे लगे।
> लेकिन इसके बाद जो कुछ
> हुआ, अशोभनीय ही हुआ।
> रात को अतिथिगृह में राजेंद्र सिंह को
> गालियां मिलीं। उनके कपड़े
> फाड़ दिये गये और अजीत समर्थकों ने
> वीपी सिंह और देवीलाल
> को विश्वासघाती और 'दगाबाज'
> बताया।

बैठक तीन बजे दोपहर में शुरू होनी थी। पर शुरू होते-होते तीन बजकर पैंतीस मिनट हो गये। पहले मधु दंडवते ने तिलक हाल से गैर विधायकों को बाहर आने की अपील की। लेकिन अपील कौन मानता? फिर मुलायम सिंह ने स्वयं गेट पर खड़े होकर गैर विधायकों को बाहर किया। बैठक तीन बजकर ३७ मिनट तक शुरू हुई। मंच पर तीनों पर्यवेक्षक सहित अजीत सिंह और मुलायम सिंह बैठे। मधु दंडवते ने एक-एक विधायक को अपने हस्ताक्षरवाली पर्ची दीं और उस पर नेता का नाम लिखने को कहा। इस प्रक्रिया में लगभग डेढ़ घंटा लगा। फिर इन्हें गिनने का काम मुख्य रूप से चिमनभाई पटेल और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया। मतदाता विधायक २१२ थे। इनमें २०४ विधायक व ८ विधान परिषद सदस्य थे। किसको कितने वोट मिले, इसका खुलासा तो किसी ने नहीं किया, पर एक विधायक के अनुसार मुलायम सिंह को १२२ और अजीत सिंह को ९० विधायकों ने अपनी पसंद माना। यह समझा जाता है कि जनता पार्टी के अधिक विधायक अजीत के साथ रहे जबकि जनमोर्चा वाले मुलायम सिंह के साथ। स्वयं अजीत गुट के सभी विधायकों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इस 'गुप्त मतदान' को पर्यवेक्षक मधु दंडवते ने सर्वसम्मत निर्णय बताया। जैसे ही छह बजकर २० मिनट पर निर्णय हुआ 'मुलायम सिंह जिंदाबाद' के गगनभेदी नारे लगे। सचिवालय में इस खुशी में शीशे भी टूटे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, अशोभनीय ही हुआ। रात को अतिथि गृह में राजेंद्र सिंह को गालियां मिलीं। उनके कपड़े फाड़ दिये गये और अजीत समर्थकों ने वीपी सिंह और देवीलाल को विश्वासघाती और 'दगाबाज' बताया। राजेंद्र सिंह के लिए कहा गया कि उन्होंने मुलायम से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए अजीत का गलत इस्तेमाल किया। १९८३ में मुलायम ने राजेंद्र सिंह को लोकदल अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता पद से हटवा दिया था।

३ दिसंबर का नजारा ९ फरवरी १९८७ से बहुत कुछ मिलता जुलता था, जब नेता विरोधी दल के पद के लिए अजीत और मुलायम सिंह समर्थकों में अपने-अपने ठीहे पर विधायकों को घसीट लाने की जंग छिड़ी थी। तब अजीत सिंह गुट लोकदल-अ की जीत हुई थी और सत्यपाल यादव नेता विरोधी दल के पद पर काबिज हुए थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद प्राप्ति की होड़ में मुलायम सिंह ने बाजी मार ली। सर्वसम्मत-चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तो बने लेकिन जद विधायकों तथा गैर विधायकों को यह कहते भी सुना गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो यह सरकार साल भर भी चल जाये तो गनीमत है।

—लखनऊ ब्यूरो

छाया : मनमोहन शर्मा

उत्तर प्रदेश

मतदाताओं ने भाजपा का भ्रम तोड़ा

२७ नवंबर की ढलती शाम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के चेहरे पर चिंता के भाव प्रकट होने लगे थे। उस समय तक चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक बयार की दिशा नियत कर दी थी। जनता दल की बढ़त और कांग्रेस को सिमटते पाकर ही उस रात तिवारी ने 'माया' से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, "लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। यदि वह परिवर्तन चाहती है, तो हम उसकी इच्छा का आदर करते हुए अपनी शक्ति और स्थिति के अनुरूप अपना दायित्व निभायेंगे।" बिना किसी लहर के गुजरने वाले इस आम चुनाव की तुलना १९६७ में हुए चुनाव से की जा रही थी। लेकिन परिणामों ने साबित कर दिया कि स्थिति उससे भी बदतर थी।

कांग्रेसी समीकरण बेअसर: १९६७ और १९६९ के चुनाव के तत्काल बाद अल्पमत में होते हुए भी कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया था। १९६७ में विपक्षी एकता न बन पाने के कारण एकल पार्टी होने का लाभ कांग्रेस को मिला था, जबकि १९६९ में कुछ आजाद उम्मीदवारों ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। दोनों बार इन परिस्थितियों का सुख स्वर्गीय चन्द्र भानु गुप्त ने मुख्यमंत्री बनकर भोगा था। इस बार कांग्रेस के सारे समीकरण जनता ने अपहृत कर लिए हैं। साझा सरकार की संभावना भी गलत साबित हुई। इस चुनाव में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद, सांप्रदायिकता, चीनी जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री की महंगाई, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा रही, लेकिन परिणाम बताता है कि असल मुद्दा सत्ता परिवर्तन का रहा। विपक्ष के किसी दल विशेष को मत देने की अपेक्षा मतदाताओं ने सत्तारूढ़ दल को हटाने में ज्यादा रुचि ली।

इसी चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की किलेबन्दी करने के लिए दूसरे वर्ग की नाराजगी मोल लेने की हद तक तुष्टीकरण की नीति अपनायी थी। हरिजनों के लिए तमाम घोषणाएं तो की ही गयीं, चुनाव से ६ माह पूर्व से सरकारी विभागों ने हरिजनों की भर्ती का व्यापक अभियान भी छिड़वाया। मुस्लिमों को गले लगाने की नीयत से ही गरमाये सांप्रदायिक माहौल को समझते हुए भी मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने का ऐलान किया, जिसका दुष्परिणाम बदायूं की निरीह जनता को भुगतना पड़ा। मुस्लिमों के प्रति बरती जा रही तुष्टीकरण की नीति से नाराज हुए हिन्दुओं के रुख को भांप कर अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला पूजन की मौन स्वीकृति देकर हिन्दुओं को मनाने की कोशिश की गयी। इस आयोजन के लिए आरोपित होने पर घबरा कर मंदिर निर्माण पर रोक लगायी, जिससे दुबारा रोष की ओर पलटी हिन्दू मानसिकता भी फनफना उठी। कांग्रेस की इस पैंतरेबाजी को शायद हर वर्ग ने बारीकी से परखा था।

प्रधानमंत्री को वोट: फतेहपुर का एक मतदान केंद्र

भितरघात ले डूबा: कांग्रेस की हार का कारण जहां आम जनता से जुड़े तमाम मुद्दे रहे, वहीं पार्टी के आपसी भितरघात का भी भरपूर कुप्रभाव रहा। जिलों-जिलों में बंटी कांग्रेस ने दूसरे गुट के टिकट पाये पार्टी उम्मीदवार को हराने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। टिकट वितरण से पनपी नाराजगी ने आग में घी का काम किया। सरकार और संगठन में तालमेल न होने से चुनावी रणनीति पुख्ता नहीं रही। सरकार के नेतृत्वकर्ता नारायणदत्त तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में चुनाव होने तक एकमत रहने की वचनबद्धता हुई, लेकिन परिणाम को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के आरोप लगाये जाने लगे। बलराम सिंह यादव ने तो हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, किंतु तिवारी इस वाक्य से परहेज कर गये। दोनों ने अपनी-अपनी पसंद के लोगों को उनकी जीत के बारे में बिना जांचे-परखे टिकट दिया। तिवारी ने जहां सतेन्द्र चंद्र गुड़िया, श्रीमती इंद्रमोहिनी, उनकी बेटी रीना कुमारी, गुलाब सेहरा, महंत सतपाल महाराज, तांत्रिक जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जैसों को टिकट दिलवाया, वहीं बलराम सिंह यादव ने अपने बेटे, भतीजे सहित राम कृपाल सिंह, शक्तिधर यादव, आजाद कुमार कर्दम, महेंद्र प्रकाश डागा जैसों को टिकट देकर उपकृत किया। इनमें से कोई विधायक न बन सका।

परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर ही इस बात की चर्चा शुरू हो गयी है कि नारायणदत्त तिवारी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराकर बुद्धिमानी नहीं की। तिवारी ने अपनी रणनीति तय करने के लिए १९८४ (संसदीय चुनाव) और १९८५ (विधानसभाई चुनाव) को आधार बनाया, जब कांग्रेस को लोकसभा की ८३ सीटें मिली थीं, पर विधानसभा में २६८ सीटें ही हासिल हो सकी थीं। राजनीतिक माहौल भांपने वालों का कहना है कि

कैसे लड़ा गया आम चुनाव?

इस बार संसदीय और विधानसभाई आम चुनाव में सत्तापक्ष और विपक्ष के मध्य फिल्मी गानों की तर्ज पर पैरोडी, नारों में एक-दूसरे की काट, पोस्टर युद्ध और हिंसक मुठभेड़ों ने पिछले चुनाव के रिकार्ड तोड़ दिये। वीडियो फिल्म और नुक्कड़ नाटकों के जरिये अपनी सफाई तथा विरोधी पक्ष की खिंचाई कर मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिशें की गयीं। जहां कांग्रेस से नाराज मतदाताओं का रुख सहज ही विपक्ष की ओर हुआ, वहीं ३०० करोड़ रुपए फूंक कर भी कांग्रेस मतदाताओं के मन-मस्तिष्क को प्रभावित नही कर सकी।

इस आम चुनाव में नुक्कड़ नाटकों को प्रचार माध्यम के रूप में अपनाया गया। इन नाटकों का आयोजन प्रमुख रूप से साम्यवादी दलों द्वारा किया गया। कानपुर की साम्यवादी उम्मीदवार सुभाषिनी अली के समर्थन में उनके समर्थकों ने जगह-जगह नुक्कड़ नाटक किये, जिसमें महंगाई, बेकारी तथा सांप्रदायिकता के साथ खेल रही सत्ता पार्टी के कारनामों को रंगकर्मियों ने उजागर करने का प्रयास किया। श्रीमती नादिरा बब्बर ने जनता दल की तरफ से राजीव गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में नुक्कड़ नाटक कर राजीव सरकार के कारनामों को सशक्त ढंग से मतदाताओं के सामने पेश किया।

वीडियो कैसेट की धूम: चुनाव की दृष्टि से बनवायी गयी वीडियो फिल्में गांव-गांव दिखायी गयीं। इस तरह के प्रचार में कांग्रेस ही आगे रही। अमेठी में कई सचल वीडियो वैन टहलती रहीं। इन फिल्मों में बीच-बीच में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के भाषण, उनकी हत्या के बाद के दृश्य और फिर राजीव गांधी की हाथ जोड़े तस्वीरें उभरती थीं। इसी तरह फतेहपुर में विश्वनाथ प्रताप सिंह का मुकाबला करने वाले कांग्रेस के हरिकृष्ण शास्त्री के लिए भी इंका हाईकमान ने कई वीडियो वैन भेजी थीं। हाथ जोड़े हुए पर्दे पर उभरने वाले शास्त्री क्षेत्र में अपने द्वारा कराये गये विकास कार्यों की गिनती कराते थे। उनके पिता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का चित्र बीच-बीच में प्रकट होता था। कांग्रेस ने जहां महेन्द्रा कंपनी के 'सस्पेंस स्टाक' से जीपों की खेप निकलवायी, वहीं सम्राट साइकिल से भी प्रचार कराकर ऊपर से लेकर नीचे तक प्रचार-पैठ बनाने का प्रयास किया।

चुनावी गीतों के कैसेट बनाने वाली कंपनियों की इस चुनाव ने पौ-बारह कर दी। फिल्मी गीतों कीं तर्ज के अलावा सर्वाधिक गीत भोजपुरी के थे। जिनकी कोई पूछ नहीं थी, उन विरहा गायकों के भी भाव लग गये। इंका के गीतों में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की स्तुति थी, तो विपक्ष के अधिकांश गीत प्रदेश के जनता दल अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम पर थे।

'बजा नगाड़ा जनता दल का' शीर्षक का यह कैसेट कांग्रेस की पोल खोलने में प्रभावी रहा। यह कैसेट बांदा निवासी अमिताभ आधार ने तैयार किया था। गीतों में वंदना वाजपेयी और भूपेश के स्वर थे। 'चलो जवानों चलो किसानों, मुलायम सिंह अब बुला रहे हैं, नौजवानों बढ़ो।' इस गीत की हंसी उड़ाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक पैरोडी बनायी 'चलो जवानों चाय पिलाने, मुलायम सिंह अब बुला रहे हैं।'

गीतों की भरमार: विपक्ष के चुनावी गीतों के मुकाबले कांग्रेसी खेमे के कैसेटों में अपनी विश्वसनीयता तथा विपक्ष को नकारा जताने का सुर-ताल था। 'ऐ वतन, ऐ वतन है मेरी धड़कन, तेरा हर ख्वाब सच करूंगा, ये है मेरा वचन।' वचनबद्धता में ढले थे, तो 'पापा कहते हैं....' फिल्मी गाने की तर्ज पर नेता कहते हैं बडा नाम करेंगे, देश का अपना ऊंचा नाम करेंगे, मगर ये तो हर कोई जाने, कि उनकी मंजिल है कुर्सियां' जैसे गीत विपक्ष की अविश्वसनीयता जता रहे थे। 'देश है अंगूठी, राजीव है नगीना, जिसने हमें सिखाया जीना-जीना-जीना' गीत हर गली कूचे में गूंजता रहा।

नारों में अपनी बात और विपक्ष को मात देने की सोच थी। अमेठी में तो राजीव गांधी के पूरे परिवार को नारों में समेट लिया गया। इन नारों में जहां राजीव गांधी की बेटी प्रियंका को अमेठी का डंका बताया गया, वहीं बेटे राहुल को विकास का बिगुल करार दिया गया। 'विकास की आंधी, सोनिया गांधी', 'भइया का भौजाई का, वोट कांग्रेस आई का' नारों के साथ राजीव के लिए राम रहीम की दुहाई भी दी गयी, 'राम रहीम दुहाई है, राजीव हमारा भाई है।' यह अलग बात है कि यह दुहाई मतदाताओं ने अनसुनी कर दी। विपक्ष की ओर के नारों में बेकारी, महंगाई, सांप्रदायिकता और दलाली के सारे आरोप कांग्रेस पर मढ़े गये। विपक्ष का यह नारा काफी चर्चित रहा, 'धृतराष्ट्र के हाथ में सत्ता, सभी तरफ अंधियारा है। हमने देखा, देख रहे हैं, यही तो उनका नारा है।'

सौतेला रवैया: कांग्रेस हर सुविधा से संपन्न होकर चुनाव मैदान में थी, जबकि विपक्ष को असुविधा का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को लगभग ५ हजार जीप-कारें, टेलीफोन की हाट लाइनें, ठहरने के लिए सरकारी आवास गृह और अन्य सरकारी सहयोग प्राप्त था, तो विपक्षी दलों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता स्थानीय बात करने के लिए भी टेलीफोन की जुगाड़ में मारे-मारे फिरते देखे गये। जिस मतदान केंद्र पर कांग्रेस को बूथ कैप्चरिंग का अंदेशा था, वहां तो अर्धसैनिक बल के जवानों की सतर्कता थी, लेकिन जहां विपक्ष को ऐसी आशंका थी, वहां होमगार्ड के सिपाही बैठे मूंगफली खाते दिखे। अमेठी में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बीएसएफ की ६, सीआरपीएफ की ७, सीआईएसएफ की ३ तथा २ कंपनी आईटीबीपी सहित लगभग २० हजार होमगार्ड और इतनी ही संख्या में प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया था। बावजूद इसके वहां बूथ कैप्चरिंग और हिंसक वारदातें हुईं तथा पुनर्मतदान की नौबत आयी।

पोस्टर युद्ध के दृश्य भी काफी रोचक रहे। इंका के पोस्टर में वीपी सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर, हेगड़े और एनटी रामाराव को कुरसी के लिए झगड़ते दिखाया गया, तो फतेहपुर की दीवारों पर चस्पा किये गये पोस्टरों में दृश्य था कि राजीव गांधी तीर कमान लिए वीपी से जूझ रहे हैं। उनके तरकश के हर तीर पर 'भ्रष्टाचार', 'बोफोर्स', 'झूठा', लिखा था और वीपी सिंह कृष्ण की तरह राजीव के तीरों को चक्र से काट रहे थे।

पक्ष-विपक्ष के दिग्गज उम्मीदवारों की जीत-हार पर लगे दांव ने सट्टा बाजार का भाव बढ़ा दिया। हापुड़ सट्टे का गढ़ है। यहां तीन बातों पर दांव लगे एक, कौन दल सत्ता में आयेगा? दो, प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा तीसरी, कांग्रेस और विपक्ष कितनी सीटें पायेगा? सट्टा बाजार में राजीव का रेट ५ पैसे तथा वीपी का रेट २५ पैसे तक चढ़ा। यही नहीं, सटोरियों ने चुनाव में घायल हुए संजय सिंह के जीवन पर भी दांव लगाया।

चुनाव में सबसे उद्विग्न वे उम्मीदवार थे, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिह्न टिकट वितरण के अंतिम समय तक रद्दोबदल की अफरातफरी के कारण नहीं मिल सका। ऐसे लगभग तीन दर्जन प्रत्याशी थे। इनमें कांग्रेस-इ के लोकसभा के एक (आंवला) तथा विधानसभा के १८ प्रत्याशी थे। जनता दल के लोकसभा में २ और विधानसभा के १५ प्रत्याशी पार्टी का चुनाव चिह्न न पा सके। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी आधा दर्जन प्रत्याशी थे। चुनाव चिह्न न पा सकने के कारण वे निर्दलीय घोषित किये गये। इन उम्मीदवारों को घर-घर जाकर यह बताने की मशक्कत करनी पड़ी कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी वे ही हैं। पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी एक भी सीट न हासिल कर सकनेवाली दूरदर्शी पार्टी के सर्वेसर्वा जय गुरुदेव ने इस बार भी अपनी सरकार बनाने का सपना संजो रखा था। शायद यही वजह थी कि

१० नवंबर को लखनऊ में अपनी सभा में उन्होंने घोषणा की कि यदि हमारी सरकार बनी, तो विदेशी औरत से शादी करनेवाले को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जायेगा।

नवीं लोकसभा तथा दसवीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियां इतनी अफरातफरी में बनायी गयीं कि उसमें मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो गये। इस कमी की ओर संकेत करते हुए बहुतों का यह आरोप रहा कि कांग्रेस ने जिन-जिन क्षेत्रों को विपक्ष का क्षेत्र माना, उन्हीं जगहों की सूचियों में मतदाताओं के नाम गायब रहे। नतीजतन इसी वर्ष हुए स्थानीय निकाय चुनाव के मतदाता, सरकार बनाने-गिराने वाले इस चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित रह गये। इन अधूरी मतदातासूचियों के कारण प्रदेश भर के लगभग १० लाख मतदाता अपने इरादे को अमल में न ला सके। प्रसिद्ध उपन्यास 'राग दरबारी' के लेखक एंव साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त चर्चित उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल एक जमाने से लखनऊ के बाशिंदे हैं। वे बताते हैं, "२२ नवंबर को मैं अपनी पत्नी गिरिजा देवी के साथ मतदान केंद्र पहुंचा, तो यह जानकर अवाक रह गया कि हम दोनों इस चुनाव में मतदाता नहीं हैं।"

सरकारी खामियां: मतदाता सूची से खारिज हुए मतदाताओं की संख्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा थी। यहां कई पुराने मोहल्लों का अस्तित्व ही सूची में गायब हो गया। हिंदी 'तार सप्तक' के सुविख्यात कवि कुंअर नारायण अपनी पत्नी श्रीमती भारती नारायण सहित इस बार की मतदाता सूची से नदारद् पाये गये। वे महानगर (लखनऊ) के पुराने बाशिंदे हैं। विख्यात रंगकर्मी राज बिसारिया और उनकी पत्नी किरन बिसारिया मताधिकार से वंचित होकर मायूस हुईं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशीय महासंत्री कलराज मिश्र राजीव सरकार पर नौजवानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहते हैं, "सरकार ने नये नवयुवक-नवयुवतियों को ४ प्रतिशत मतदान में साझेदारी के आंकड़े दिये थे, जबकि संसदीय तथा विधानसभाओं के चुनाव में ऐसे मतदाताओं की संख्या एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं थी।" मतदाता सूची की इस त्रुटि को महज निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसी वर्ष हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रयोग की गयी मतदाता सूचियों में सबके नाम मौजूद थे।

—सुरेश

यदि तिवारी ने १९७७ को याद कर लिया होता, तो शायद कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। तब लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से खारिज हुई कांग्रेस को विधान सभा में ४७ सीटें मिल गयी थीं। यदि दोनों चुनाव अलग-अलग होते, तो एक चुनाव के परिणाम को देखकर दूसरे चुनाव में जीत के लिए नयी रणनीति और गलतियों को सुधारने की दौड़-भाग की जा सकती थी। इस संबंध में तिवारी तर्क देते हैं, "अलग-अलग चुनाव कराने में पैसों का खर्च बढ़ जाता जो मुझे उचित नहीं जान पड़ा।" लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि केवल प्रचार में ३०० करोड़ रुपए फूंककर कांग्रेस ने कौन-सा खर्च बचाया है?

तिवारी सरकार के ४२ मंत्रियों और संगठन के १४ पदाधिकारियों को मैदान में उतारा गया था। इनके ३४ मंत्री जनता द्वारा नकार दिये गये और संगठन के पदाधिकारियों में केवल ३ ही जीत सके। मंत्रियों की हार तो उनके कारनामों की वजह से हुई, किंतु संगठन के पदाधिकारियों की पराजय अनेक क्षेत्रों में उनकी कोई टिकाऊ जमीन न होने के कारण हुई। सूत्रों के अनुसार लोकपति त्रिपाठी, गोपीनाथ दीक्षित, अम्मार रिजवी, नरेंद्र सिंह, श्याम सूरत उपाध्याय, बलदेव सिंह आर्य जैसे मंत्रियों की हार के लिए उन्हीं के विभागीय कर्मचारियों ने मनौती मानी थी और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हराने की कसम खा रखी थी। नरेंद्र सिंह तो निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा धकिया दिये गये। नारायणदत्त तिवारी की जीत ही ऐसी थी जिसमें कोई संशय नहीं था। खुद वे भी अपनी जीत पक्की मानते थे। नामांकन के बाद एक बार भी अपने क्षेत्र में न जाना इसका प्रमाण है। अमेठी की जनता ने राजीव गांधी सहित अपने संसदीय क्षेत्र की पांचों विधानसभाई सीटों पर कांग्रेस को जिताकर राजीव गांधी के प्रति अहसानमंद होने का सबूत दे दिया। इसी के साथ संजय सिंह जैसे दिग्गज को हरा कर यह भी जता दिया कि यहां राजीव गांधी का विरोध कारगर नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेठी के राजकुमार संजय सिंह १९८५ में कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से प्रदेश में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते थे।

सत्ता का हस्तांतरण: नारायण दत्त तिवारी नये मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए

कांग्रेस की साख गिरी: पिछले ३ चुनाव पर यदि नजर डाली जाये, तो यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की साख लगातार गिरी है। १९८० में प्रदेश में ३७.७८ प्रतिशत मत पाकर ३०६ स्थानों पर जीतने वाली कांग्रेस १९८५ में अपने पक्ष में हवा होने के बावजूद ३९.३१ प्रतिशत मत पाकर भी २६८ सीटें ही हासिल कर सकी थी। इस बार ४१९ घोषित परिणामों में कांग्रेस-इ की सीटों की यह संख्या ९२ पर ही सिमट गयी। १९८० की अपेक्षा कांग्रेस ने १९८५ में मात्र गढवाल में ४, बरेली और मुरादाबाद मंडलों में क्रमश: एक-एक सीट की बढ़त हासिल की थी। इसके विपरीत अन्य मंडलों की अपनी पुरानी सीटों से उसे हाथ धोना पड़ा था। सबसे ज्यादा तो उसे वाराणसी मंडल में हानि हुई थी, जहां १९८५ में उसके हाथ से १३ सीटें निकल गयी थीं। गढ़वाल, बरेली, और मुरादाबाद में १९८५ में बढ़त हासिल करनेवाली कांग्रेस इस बार तीन चौथाई स्थान गंवा बैठी। वाराणसी मंडल में तो वह ४६ में केवल ३ स्थान पर सिमट कर रह गयी। गढ़वाल मंडल के चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, बरेली मंडल के बरेली जिले और पीलीभीत, आगरा मंडल के आगरा जिले, झांसी के जालौन और ललितपुर, लखनऊ के उन्नाव, मेरठ मंडल के मेरठ जिले तथा वाराणसी मंडल के वाराणसी जिले में कांग्रेसियों का पूरी तरह सफाया हो गया। १९७७ में ३७ जिलों में कांग्रेस शून्य रही थी। तब कांग्रेस ने प्रदेश भर में सबसे ज्यादा सीटें जौनपुर में (१० में ७) जीती थी, जबकि इस बार यह संख्या मात्र एक है।

संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश से लड़े ११ केंद्रीय मंत्रियों में केवल ब्रह्मदत्त, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद और कल्पनाथ राय ही

अपनी जीत दर्ज कर सके। १९८४ में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए ८ सांसदों को इस बार जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें केवल घासी (आजमगढ़) से राजकुमार राय के अलावा सभी ने अपनी पूर्व पार्टी के दिग्गजों को परास्त किया। जबकि विपक्ष से कांग्रेस में घसीटे गये रामनरेश यादव और चंद्रजीत यादव जैसों को कभी अपने रहे लोगों से ही शिकस्त खानी पड़ी। जनता दल ने प्रदेश के ५ विपक्षी विधायकों को संसद का टिकट दिया था और वे सब जीते। इस चुनाव में एक विशेष बात यह रही कि इस बार मतदाताओं ने पार्टी के साथ उम्मीदवार के व्यक्तित्व को भी तौला। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के ब्रह्मदत्त, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, धर्मराज सिंह, आनंद सिंह, कल्पनाथ राय सरीखे लोग जीते, मगर शीला दीक्षित, गंगाराम, सतपाल महाराज, सतेंद्र गुड़िया, भीष्मदेव दुबे, नरेशचंद्र चतुर्वेदी जैसों की हार हुई। कांग्रेस के दिग्गजों के साथ-साथ जनता दल के भी कई धुरंधर जनता के हाथ पटकनी खा गये। इनमें प्रदेश के पूर्व नेता विरोधी दल तथा वर्तमान में जनता दल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, नेता विरोधी दल सत्यपाल सिंह, प्रधान महासचिव संजय सिंह और प्रमुख नेता मोहन सिंह प्रमुख हैं। इनमें सत्यपाल सिंह यादव संसदीय चुनाव जीत गये।

कांग्रेस-विरोधी लहर: इस चुनाव में कांग्रेस-विरोधी लहर तो थी, लेकिन लहर का वेग समझ नहीं आ रहा था। जनता द्वारा बिना किसी आवेग के लिए गये सतर्क फैसले में न सांप्रदायिकता को जगह मिली, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद और न ही माफिया सरगनाओं को। चुनाव से पूर्व राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मुद्दा प्रभावी समझा गया था, किंतु परिणामों ने इस समझ को निर्मूल साबित किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस चुनाव के जरिये हिन्दू-मुस्लिमों ने यह जता दिया है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को कुरेद कर उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकना अपने हाथ जला लेना है। कानपुर से माकपा की सुभाषिनी अली और विवाद के केंद्र जिला फैजाबाद में भाकपा के मित्रसेन यादव संसद का चुनाव न जीत पाते, यदि राम जन्मभूमि बाबरी-मस्जिद का मुद्दा चुनाव में प्रभावी होता। कांग्रेस के संसदीय उम्मीदवारों में कानपुर से नरेशचंद्र चतुर्वेदी तथा सलेमपुर (देवरिया) से राम नगीना मिश्र अयोध्या में राम मन्दिर बनने का खुला समर्थन कर चुनाव लड़े। विश्व हिन्दू परिषद ने राम नगीना मिश्र को समर्थन की घोषणा भी कर दी थी। बावजूद इसके दोनों बुरी तरह पराजित हो गये। फैजाबाद के ४ विधानसभा क्षेत्रों में खड़े भाजपा प्रत्याशियों की हार भी इसका सबूत है। माफिया सरगना कहे जाने वालों में मात्र इंका उम्मीदवार हरिशंकर तिवारी ही जीते, हालांकि उनकी जीत क्षेत्र में व्यवहार कुशलता के कारण हुई।

चौथी ताकत: इस चुनाव में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं। राजनीति में चौथी ताकत के रूप में उभरी इस पार्टी ने कई वर्षों की मशक्कत के बाद असर दिखाया है। प्रदेश में लोकसभा की २ तथा

राम जन्मभूमि मुद्दा निष्प्रभावी रहा

चुनाव से पूर्व तक राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सर्वाधिक प्रभावी माना जा रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों को यकीन था कि चुनाव परिणाम इसी मुद्दे की धुरी के इर्द-गिर्द घूमेंगे। उनकी धारणा थी कि हिन्दू-मुस्लिम कट्टरवाद का तांडव, चुनाव में नये गुल खिलायेगा। यही कारण था कि जिसे भी मौका मिला, वह 'मंदिर-मस्जिद' के इस विवाद से पनपी सांप्रदायिकता पर सियासी रोटियां सेंकने से नहीं चूका। लेकिन चुनाव परिणाम सामने आते ही यह स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं ने अपने वोटों को सांप्रदायिकता की हुण्डी नहीं बनने दिया।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा था कि वह हिन्दू मानसिकता को उभारकर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। चुनाव परिणामों ने इस आरोप का खण्डन किया है। राम जन्मभूमि मुद्दे के केंद्र बिंदु फैजाबाद जिले की संसदीय सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जीत इसका ज्वलंत उदाहरण है। ईश्वर व धर्म को न माननेवाले साम्यवादी दल के प्रत्याशी मित्र सेन यादव की यहां से विजय यह स्पष्ट करती है कि मतदाताओं पर धर्म या सांप्रदायिकता की लहर का कोई असर नहीं था। यदि असर होता, तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी की जीत तो नहीं ही होती।

ऐसे तमाम उदाहरण हैं। कानपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगतवीर द्रोण के बारे में कहा गया था कि हिन्दुत्व की लहर के चलते उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन माकपा प्रत्याशी सुभाषिनी अली ने उन्हें ५० हजार से भी अधिक मतों से पराजित किया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के मुद्दे की सुगबुगाहट सबसे अधिक रही। लेकिन यहां केवल कैसरगंज (बहराइच) संसदीय सीट ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रुद्रसेन चौधरी को मिल सकी। यह सीट तो वैसे भी भाजपा (जनसंघ) की ही रही है। राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर विवाद का बीज बोने वाले तथा आजादी से पूर्व फैजाबाद के जिलाधिकारी रहे केके नायर की पत्नी शकुंतला नायर कैसरगंज संसदीय सीट से जीतती रहीं। इसलिए यहां भी हिन्दुत्व की हवा जैसी कोई बात नजर नहीं आयी।

विश्व हिन्दू परिषद ने गत ९ नवंबर को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की, तब इस धारणा ने काफी तूल पकड़ा था कि हिन्दू मतों के जरिये भाजपा को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। यदि वास्तव में ऐसा होता, तो कम से कम फैजाबाद जिले की विधानसभाई सीटों पर भाजपा को ऐसी दुर्दशा न झेलनी पड़ती, जो उसने झेली।

'मंदिर-मस्जिद' विवाद को लेकर देश-विदेश में चर्चित फैजाबाद जिले के कुल ९ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से ५ पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें कटेहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गयी। यह सीट जनता दल के रवीन्द्र नाथ तिवारी को मिली और बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर रही। जलालपुर की सीट पर भाजपा प्रत्याशी तीसरे तथा जहांगीरगंज में चौथे स्थान पर रहे। इन स्थानों पर क्रमश: बसपा के रामलखन वर्मा तथा जनता दल के अरुण कुमार विजयी रहे। सोहावल विधानसभाई सीट पर भी भाजपा तीसरे नंबर पर रही। इस सीट से जीते जनता दल के अवधेश प्रसाद का मुकाबला बसपा प्रत्याशी से था। भाजपा के लिए केवल एक सीट 'अयोध्या' ऐसी रही, जहां उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह सीट भी जनता दल के जयशंकर पांडेय को मिली।

उक्त विधानसभाई सीटों पर भाजपा की यह दुर्गति तब हुई, जबकि रुदौली को छोड़कर फैजाबाद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हिन्दू मतदाताओं की संख्या किसी भी प्रत्याशी को जिताने का सामर्थ्य रखती है। फैजाबाद के चुनाव परिणामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि देश और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भाजपा को हिन्दुत्व की लहर का कितना लाभ मिला होगा!

उक्त चुनाव परिणामों के विश्लेषण के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मुद्दे ने हिन्दू मानसिकता को उभारा जरूर, लेकिन इतना नहीं कि मतदाताओं के इरादे को प्रभावित कर सके।

—राजीव सक्सेना,

मप्र जैसी सफलता नहीं मिली : भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी

जितनी आशा थी, उतनी सीट भाजपा को नहीं मिली। इसकी वजह कार्यकर्ताओं का छिन्न-भिन्न होना है। पार्टी के नाम पर मठाधीशी करने वाले नेताओं में इतनी कूबत नहीं थी कि वे पार्टी में रुझान रखनेवालों का मत पक्ष में गिरवा सकें। जो कार्यकर्ता पहले लइया-चना खाकर घर-घर से वोट निकलवाता था, उसने इस बार इन नेताओं की मठाधीशी से क्षुब्ध होकर केवल अपने मत को पार्टी की कटिबद्धता में डाला।

विधानसभा की १३ सीटों पर कब्जा करके उसने अन्य राजनीतिक दलों को चौकन्ना कर दिया है। संसदीय चुनाव में वह लगभग आधा दर्जन स्थानों पर तथा विधानसभा में करीब २५ स्थानों पर दूसरे नवबर पर रही तथा ७३ स्थानों पर तीसरे नंबर पर रहकर इस पार्टी ने विजयी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी है। लगभग एक दर्जन से अधिक जगहों पर तो वह जीतते-जीतते रह गयी। इस पार्टी के सर्वेसर्वा कांशीराम यद्यपि जीत का सेहरा नहीं बांध सके, लेकिन उनकी हमेशा से हुंकारी जाने वाली यह बात कि एक दिन उनकी पार्टी की भी सरकार बनेगी, में दम नजर आने लगा है। बसपा ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध मारी है। कांग्रेस की भारी शिकस्त की एक वजह बसपा भी है। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने वोट के लिए जो फसल बोयी थी, उसे बसपा ने अधिया लिया।

भाजपा का भ्रम : यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। इस बार भाजपा ५७ स्थान पाकर ३४ जगहों पर दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने बहुत तेजी से जनता का रुझान अपनी ओर खींचा है। चुनाव के समय तक भाजपा पर यह आरोप लगता रहा कि वह हिन्दू उग्रवाद के बल पर मैदान में है। लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि यह आरोप महज सियासी ही थे। उदाहरण के तौर पर फैजाबाद जिले को लिया जा सकता है, जो मंदिर मस्जिद विवाद का केंद्र स्थल है। यहां भाजपा ने ४ जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। इनमें से कोई भी विजयी नहीं हुआ। यहां तक कि अयोध्या में भी उसकी शिकस्त हुई। लोकसभा में पार्टी ने ८ स्थान पाये हैं। फिर भी वह अपने १९६७ के विधानसभा रिकार्ड तक नहीं पहुंच सकी, जब उसने ९८ स्थान पाकर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की हैसियत बनायी थी। वैसे यह कहना ज्यादा उचित होगा कि इस बार का परिणाम बहुत कुछ १९७४ से मिलता जुलता है, जब भाजपा ६१ स्थानों पर विजयी हुई थी।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि इस बार जितनी आशा थी, उतनी सीट भाजपा को नहीं मिली। इसकी वजह कार्यकर्ताओं का छिन्न-भिन्न होना है। पार्टी के नाम पर मठाधीशी करने वाले नेताओं में इतनी कूवत नहीं थी कि वे पार्टी में रुझान रखनेवालों का मत पक्ष में गिरवा सकें। जो कार्यकर्ता पहले लइया-चना खाकर घर-घर से वोट निकलवाता था, उसने इस बार इन नेताओं की मठाधीशी से क्षुब्ध होकर केवल अपने मत को पार्टी की कटिबद्धता में डाला। पार्टी को समर्पित केशरीनाथ त्रिपाठी, राजनाथ सिंह और राजेंद्र गुप्त जैसे कर्मठ नेता अब पीछे ढकेल दिये गये हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में लखनऊ में सबसे अधिक सीटें जीतकर भी नगर प्रमुख की कुरसी न पा सकना पार्टी के नेताओं की अदूरदर्शिता ही कही जायेगी।

जनता दल से अपेक्षा : जनता ने एक बार फिर विपक्ष को संवरने का मौका दिया है। उसे जनता दल की सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। १९७७ की जनता सरकार की गलतियों को न दोहराने के वायदे के साथ मुलायम सिह यादव मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। हालांकि उनकी सरकार में घटकवाद की वे सारी बीमारियां मौजूद हैं, जो जनता शासन में थी। राजेंद्र सिह, सत्यपाल यादव और संजय सिह की हार ने मुलायम सिह यादव को मुख्यमंत्री बनने के रास्ते साफ किये, लेकिन अजीत सिह और उनके समर्थकों का विरोध अभी से करवटें लेने लगा है। खुद अजीत सिह ने अपने कुछ विधायकों और समर्थकों द्वारा अपना नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलवाया था। यही मुद्दा सरकार के गठन में गतिरोध का कारण बना। एक बार तो ऐसा लगा कि अजीत समर्थक विधायक कहीं विद्रोह न कर दें, लेकिन वक्त की नजाकत समझकर सभी घटकों ने टकराव का रास्ता छोड़ देना ही उचित माना। लेकिन यह विरोध कब उग्र हो जायेगा, अभी तक की स्थितियां देखते हुए कहा नहीं जा सकता। पूरे परिणाम आने से पूर्व ही लोकदल-अ और लोकदल -ब के अजीत और मुलायम सिह के समर्थकों की लामबंदी शुरू हो गयी थी। मुलायम सिह समर्थक राजभवन कालोनी स्थित पार्टी दफ्तर में एकत्र हुए, तो अजीत समर्थक तथा मुलायम सिह के घोर विरोधी जनता दल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिह ने माल एवन्यू स्थित अपने निवास पर बैठक बुलायी। नजारा १९८७ की तरह था, जब नेता विरोधी दल के चयन को लेकर अजीत सिह और मुलायम सिह समर्थक विधायकों की अपने-अपने ठीहे पर मौजूदगी दिखाकर शक्तिपरीक्षण दर्शाया गया था।

दसवीं विधानसभा के चुनाव के जरिये सरकार बनाने के लिए निर्वाचित विपक्ष को मतदाताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि 'या तो जनता का हित करो या फिर गद्दी छोड़ो।' चुनाव से पहले की समस्याएं नयी सरकार के लिए चुनौती बनकर खड़ी होंगी। इसके अलावा विपक्ष की सरकार को उन वायदों को भी पूरा करना होगा जो चुनाव के दौरान उसने जनता से किये हैं। इस सरकार को दो चुनौतियों का सामना करना है, पहली तो राजनीतिक चुनौती होगी, जो सरकार के अस्तित्व के लिए ही प्रश्नचिह्न के रूप में सदा मौजूद रहेगी और दूसरी चुनौती होगी काम करने की। इस अग्निपरीक्षा से यदि वह बाहर आ गयी, तो यह सरकार कुंदन की तरह चमक कर स्थायित्व पा लेगी; पर यदि घटकवाद ने पुनः सिर उठाया, तो इस बार उखड़ी विपक्षी सरकार सत्ता पाने के लिए कई वर्षों तक केवल प्रयास ही करती रह जायेगी।

—अजय कुमार और सुरेश द्विवेदी

बिहार

जगन्नाथ मिश्र को कुरसी कैसे मिली ?

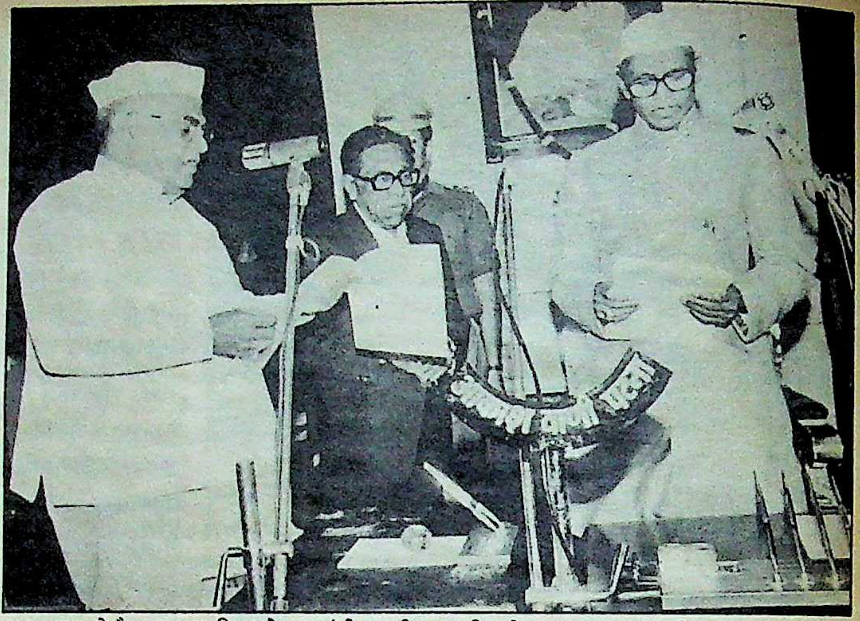

इम्तहान आगे है : जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए जगन्नाथ पहाड़िया

ग्रह-नक्षत्रों की भाव-भंगिमा पर अटूट आस्था रखनेवाले डा० जगन्नाथ मिश्र का सबसे प्रिय अंक छह रहा है। पहले वे जब दो बार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी लगभग सभी गाड़ियों का नंबर छह अंक का ही हुआ करता था। वाकई इसके पीछे चाहे जो भी ज्योतिषीय सचाई रही हो, पर इतना तो अवश्य है कि जगन्नाथ मिश्र के राजनीतिक जीवन में छह अंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सत्ता से लगभग छह वर्षों तक बाहर रहने के बाद आखिरकार विगत ६ दिसंबर की शाम जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुरसी पर काबिज होने में कामयाब हो गये। सत्ता से वंचित होने के बाद लगातार अपनी पार्टी के आलाकमान से छायायुद्ध लड़नेवाले जगन्नाथ मिश्र को बिहार का सबसे कीमती सिंहासन अब कभी नसीब भी होगा, इस संभावना पर अभी कुछ माह पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। कांग्रेस के जगन्नाथ-विरोधी दिग्गजों की जमात पूरे आत्मविश्वास से दावा करती फिरती कि जब तक राजीवजी की सत्ता है, जगन्नाथ मिश्र बिहार की सत्ता में आने की बात भूल जायें और सचमुच यही हुआ। राजीव गांधी जब तक सत्ता में रहे, तब तक जगन्नाथ मिश्र सत्ता के हाशिये तक भी फटक नहीं सके। लोकसभाई चुनाव में कांग्रेस की भीषण हार के बाद जगन्नाथ मिश्र के राजनीतिक विरोधियों को यह साफ दिखाई दे गया कि बिहार की बेशकीमती कुरसी के पास जगन्नाथ मिश्र पहुंच चुके हैं और अब उन्हें इस पर बैठने से रोक पाना असंभव है।

१४ अगस्त, १९८३ को जब जगन्नाथ मिश्र अपदस्थ किये गये थे, उन दिनों भी राजीव गांधी सत्ता में नहीं थे। बस कुछ ही माह पहले वे कांग्रेस के महासचिव हुए थे और हिमाचल प्रदेश तथा बिहार के सांगठनिक मामलों को देखने की विशेष जिम्मेदारी उन्हें दी गयी थी। सक्रिय राजनीति की दहलीज पर आते ही राजीव गांधी इस बात के लिए व्यग्र हो उठे थे कि कांग्रेसशासित प्रांतों से ऐसे मुख्यमंत्रियों को चलता कर दिया जाये जो जोड़-तोड़ तथा दांव-पेंच के दम पर सत्ता-संचालन करते हैं। राजीव गांधी की इस राजनीतिक सफाई के अभियान के सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रामलाल शिकार हुए। फिर आयी बिहार में जगन्नाथ मिश्र तथा राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया की बारी। उस समय राजीव के प्रमुख सलाहकारों में अरुण नेहरू हुआ करते थे। इन सलाहकारों ने राजीव गांधी के मन में यह बात भी सफलतापूर्वक जमा दी कि कांग्रेसशासित प्रांतों के मुख्यमंत्री स्व० संजय गांधी के विश्वासपात्र रहे हैं और ये लोग उन्हें कभी नेता नहीं मानेंगे। अर्जुन सिंह ने तो उस समय किसी तरह राजीव गांधी के पास शिकार होने के पहले ही अपनी गोट जमा ली थी, पर जगन्नाथ मिश्र और जगन्नाथ पहाड़िया सरीखे मुख्यमंत्री इस संदेह के दंड से बच नहीं सके।

अभयदान : वाकई संजय गांधी का अपार अनुग्रह जगन्नाथ मिश्र पर था। एक बार पटना हवाई अड्डे पर आयोजित कांग्रेस की सभा में संजय गांधी ने यहां तक कह दिया था कि आनेवाले बीस-पच्चीस सालों तक बिहार में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संजय गांधी के इस 'अभयदान' के बाद जगन्नाथ मिश्र से क्षुब्ध टोली की बोलती ही बंद हो गयी थी। यों कमोबेश १९८२ तक जगन्नाथ मिश्र की सत्ता पर दूर-दूर तक कोई आंच नहीं थी १९८१ में जब भागलपुर आंखफोड़ कांड को लेकर बावेला मचा या फिर बिहार प्रेस बिल के विवाद ने तूल पकड़ा, तो श्रीमती गांधी इन प्रसंगों पर चुप रही थीं। राजनीतिक खिलाड़ी भांप गये कि श्रीमती गांधी के पास जगन्नाथ मिश्र का खूंटा अभी भी मजबूत है। पटना अरबन कोआपरेटिव बैंक के केस को लेकर जब जगन्नाथ मिश्र अदालती विवाद में घसीटे जा रहे थे, तब ऐन मौके पर श्रीमती गांधी ने जगन्नाथ मिश्र को अपना प्रतिनिधि बनाकर रूस भेजा और सबको जता दिया कि इन विवादों से जगन्नाथ मिश्र की राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़नेवाला। पर १९८३ से जगन्नाथ मिश्र की सत्ता की दशा तेजी से बिगड़ने लगी। १९८३ के फरवरी माह में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के ग्यारह मंत्रियों को एक झटके में निकाल दिया। निकाले गये इन मंत्रियों की जमात में ललितेश्वर प्रसाद शाही सरीखे राजनीतिक धुरंधर थे। इन विक्षुब्धों को खुलकर दिल्ली में जेहाद छेड़ने का मौका मिल गया। उस समय माखनलाल फोतेदार ने एक वरिष्ठ विक्षुब्ध नेता से कहा भी कि आप लोग अब तक मंत्री पद की सुनहरी जंजीर में जकड़े हुए थे। जगन्नाथ मिश्र ने आप लोगों को आजाद कर अपने को संकट से जकड़ लिया है। श्रीमती गांधी से सीधे संपर्क में होने के कारण जगन्नाथ मिश्र फोतेदार या अरुण नेहरू सरीखे लोगों को कभी नजर में नहीं लगाते थे। लिहाजा, दिल्ली दरबार में भी जगन्नाथ-विरोधी एक मंडली तैयार हो गयी थी। आखिरकार बिहारी विक्षुब्धों तथा राजीव गांधी के इर्द-गिर्द उग आयी दिल्ली दरबार की नवोदित मंडली ने राजीव गांधी को

इस बात के लिए राजी कर लिया कि जगन्नाथ मिश्र को जाना ही चाहिए। उस समय जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के साथ केंद्र के भेदभाव की भी कुछ सार्थक बातें उठायी थीं। इसको भी काफी तूल दिया गया कि जगन्नाथ मिश्र तो केंद्र को खुली चुनौती दे रहे हैं और इस तरह बोल रहे हैं जैसे कोई विपक्षी नेता बोलता है। यह सचाई थी कि श्रीमती गांधी जगन्नाथ मिश्र के प्रति अंत तक काफी नरम रहीं। वे इस मैथिल ब्राह्मण नेता के राजनीतिक कला-कौशल और क्षमता को समझती थीं। पर एकबारगी श्रीमती गांधी के निकट भी ऐसा वातावरण उपस्थित किया गया कि श्रीमती गांधी ने भी जगन्नाथ मिश्र के सत्ता-पराभव को स्वीकृति दे दी।

उस समय बिहार विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या १९३ थी। उनमें लगभग १२५ विधायक जगन्नाथ मिश्र को सत्तांच्युत किये जाने के जबर्दस्त खिलाफ थे। उस समय की विधानसभा में ३६ ब्राह्मण विधायक तथा २६ मुस्लिम विधायक थे जो बिलकुल इंकलाब बोलने को तैयार थे। ये विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षक के समक्ष राजभवन में परेड तक करने को उतारू थे। जगन्नाथ मिश्र भी इस उत्साह में थे कि सत्ता से तो वे जा ही रहे हैं, पर विधायक दल में अपना समर्थन तो वे साबित कर दें। जगन्नाथ मिश्र ने तुरंत अपने समर्थक विधायकों की जमात को शांत किया था और वे राज्यपाल को त्यागपत्र दे आये थे। दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में प्रणब मुखर्जी तथा अरुण नेहरू को भेजा गया था। अरुण नेहरू राजीव गांधी के खास दूत थे और प्रणब मुखर्जी को इसलिए भेजा गया था, कि जगन्नाथ मिश्र अगर बगावती मूड में आये, तो वे उन्हें रोक सकें।

नेतृत्व का नेपथ्य: नेता-चुनाव के पूर्व सत्येंद्र सिंह, भजनलाल, दरबारा, मल्लू के साथ जगन्नाथ मिश्र

जगन्नाथ मिश्र की जगह चंद्रशेखर सिंह को सिंहासन पर बिठाकर दिल्ली लौटने के बाद अरुण नेहरू ने दिल्ली दरबार में यह बात साबित करने की सफल कोशिश की कि जगन्नाथ मिश्र कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। लिहाजा सत्ता गंवाने के बाद भी जगन्नाथ मिश्र चैन से नहीं रह सके। पटना से दिल्ली तक उनके विरुद्ध वातावरण निरंतर गर्म होता गया। जगन्नाथ विरोधी यह समझते थे कि बहुत मुश्किल से वे इस व्यक्ति को कुरसी से उतारने में कामयाब हुए हैं और अगर यह व्यक्ति दुबारा कुरसीनसीं हो गया, तो सभी के लिए सांसत कर देगा। इसलिए हाल के दिनों में भी आपस में तकरार करते रहते कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ऐसे मौके पर फौरन आपसी झगड़ा खतम कर एक हो जाते थे, जब जगन्नाथ मिश्र के फिर से किसी रूप में राजनीतिक महत्ता में आने की बात सामने पड़ जाती थी। जगन्नाथ मिश्र ने सत्ता से हटने के बाद अपने 'जन जागरण अभियान' का बिगुल फूंक दिया। जगन्नाथ मिश्र ने यह ठान लिया कि 'गणेश परिक्रमा' की राजनीति के बजाय वे जनाधारित राजनीति करेंगे और एक-न-एक दिन फिर अपनी खोई हुई सत्ता हासिल करके दम लेंगे। जगन्नाथविरोधी राजनीतिज्ञों की जमात ने यह बात दिल्ली दरबार में जोर-शोर से पहुंचानी शुरू कर दी कि जन-जागरण के जरिये जगन्नाथ मिश्र आलाकमान को धमकी दे रहे हैं। दिल्ली दरबार में यह तर्क तेजी से चल गया। पर इन तमाम विवादों के बावजूद श्रीमती गांधी का कोप कभी जगन्नाथ मिश्र पर प्रकट नहीं हुआ। चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध जगन्नाथ मिश्र ने जमकर हल्ला बोल रखा था। जगन्नाथ मिश्र ने यह शर्त रख दी थी कि चंद्रशेखर सिंह के अलावा वे किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में कबूल कर लेंगे। लिहाजा १९८४ में विधानसभाई चुनाव के बाद विवश होकर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सिंह को केंद्र में बुला लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री की कुरसी से चंद्रशेखर सिंह को संतोष करना पड़ा था। अब बिहार के सिंहासन पर बिठाये गये बिन्देश्वरी दुबे। दुबे को गद्दी सौंपने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि ब्राह्मण होने के कारण दुबे ब्राह्मण राजनीति में जगन्नाथ मिश्र को कमजोर कर देंगे। दुबे से जगन्नाथ मिश्र की फिर ठन गयी। दिल्ली दरबार को प्रसन्न करने के लिए दुबे ने भी जगन्नाथ मिश्र पर बढ़-चढ़कर वार करना शुरू किया। इसी युद्ध के क्रम में जगन्नाथ मिश्र के पटना स्थित 'ललित नारायण मिश्र सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान' का सरकारी अधिग्रहण भी दुबे ने करवा दिया। लगभग ढाई वर्ष तक बिन्देश्वरी दुबे सत्ता में इसीलिए बरकरार भी रह सके कि वे जमकर जगन्नाथ मिश्र पर हमला कर रहे थे। पर सहकारिता घोटाले और प्रदेश की बदहाली दुबे राज में जब हद तक पहुंच गयी, तो आलाकमान को भी यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि महज जगन्नाथ मिश्र को तबाह करने के लिए पूरे प्रदेश को और अधिक तबाह करना महंगा पड़ेगा। लिहाजा, दुबे का बिहार की सत्ता से पत्ता साफ हो गया। पर दुबे को केंद्रीय मंत्री की इनामी कुरसी थमा दी गयी, ताकि यह न कहा जा सके कि जगन्नाथ मिश्र से टकरा कर दुबे कहीं के न रहे।

दुबे की जगह आजाद: दुबे की जगह अब मुख्यमंत्री बनाकर उतारे गये भागवत झा आजाद। आजाद को भी भेजने के पीछे यही मकसद था कि स्वयं मैथिल ब्राह्मण होने के कारण आजाद जगन्नाथ मिश्र को और महंगे पड़ेंगे। पर आजाद को अपदस्थ करने में जगन्नाथ मिश्र को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यों मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही आजाद ने दिल्ली दरबार में लाबी कर जगन्नाथ मिश्र को राज्यसभा में भेजने का इंतजाम कर दिया, ताकि वे निष्कंटक राज कर सकें। १९८८ के मार्च माह में जगन्नाथ मिश्र राज्यसभा के सदस्य बनाये गये। शुरू में तो जगन्नाथ-समर्थकों को भी यह विश्वास नहीं था कि प्रदेश की राजनीति से राज्यसभा में जाने के लिए जगन्नाथ मिश्र राजी होंगे। पर आश्चर्यजनक रूप से जगन्नाथ मिश्र राज्यसभा की सदस्यता के प्रस्ताव पर सहमत हो गये थे। ठीक डेढ़ साल पहले जब राजीव गांधी ने उन्हें प्रस्ताव भिजवाया था कि वे राज्यपाल या राजदूत का कोई पद स्वीकार कर लें, तो जगन्नाथ मिश्र राजी नहीं हुए थे। साल लगते-लगते आजाद के खिलाफ इंका विधायकों ने सड़क पर उतर कर हल्ला बोल दिया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बिंदेश्वरी दुबे, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अनवर सरीखे नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा में इस विद्रोह को और हवा दे दी। ऐसे मौके पर जगन्नाथ मिश्र ने चतुराई की और 'आजाद हटाओ अभियान' में सीधे मोर्चे पर स्वयं नहीं आये। उन्होंने राजीव गांधी को बखूबी जताया कि उनके निर्णयों के विरुद्ध उठे माहौल को वही लोग हवा दे रहे हैं जिन पर वे अब तक भरोसा करते आये थे।

दरअसल, राजीव गांधी ने बिंदेश्वरी दुबे सरीखे नेताओं को बिहार की बगावत को बुझाने भेजा था। पर इन नेताओं ने ठीक इसके विपरीत पटना में भूमिका निभायी। राजीव तारिक के

औपचारिकता का प्रदर्शन : सदाकत आश्रम में इंका विधायक दल के नेता का चुनाव

रवैये से भी क्षुब्ध थे। आजाद को तो पद से जाना ही पड़ा, पर जगन्नाथ मिश्र इस घटना के बाद से राजीव गांधी के विश्वास के दायरे में आंशिक रूप से आ गये। लिहाजा आजाद की जगह मुख्यमंत्री पद हेतु सत्येंद्रनारायण सिंह के नाम की घोषणा के पूर्व आलाकमान ने जगन्नाथ मिश्र को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। यों आजाद के हटने के बाद यह भी मुहिम जोरं-शोर से चली थी कि क्यों न जगन्नाथ मिश्र को ही सत्ता सौंप दी जाये। थोड़ी देर के लिए राजीव गांधी इस पर सहमत हो भी गये थे, पर फिर जगन्नाथ-विरोधियों ने उन्हें समझाया कि वीपी सिंह की काट में एक राजपूत मुख्यमंत्री अवश्य होना चाहिए। मध्यप्रदेश में अर्जुन सिंह के हटने के बाद माधवराव सिंधिया तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे। लिहाजा, बिहार में सत्येंद्र नारायण सिंह को सत्ता सौंप दी गयी। सत्येंद्र नारायण सिंह भी जगन्नाथ मिश्र से सदैव सशंकित रहे, क्योंकि स्व० चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे तथा भागवत झा का प्रसंग उनके सामने था। लिहाजा, सत्येंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के जगन्नाथ-विरोधी मोर्चे को शह देना शुरू किया। रोज-ब-रोज जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध मुहिम तेज होने लगी। सचमुच यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री के बजाय विक्षुब्ध अभियान बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चलना शुरू हुआ था। जगन्नाथ मिश्र भी चूके नहीं। उन्होंने सत्येंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाया कि प्रशासन पर सरकार की लगाम ढीली है। इस तरह घात-प्रतिघात का दौर चलते-चलते लोकसभाई चुनाव के मुकाम तक आ गया। चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी व पुत्रवधू हार गयीं, भागवत झा आजाद, रामलखन सिंह यादव, केके तिवारी सरीखे खिलाड़ी चित्त हो गये। लिहाजा, इस अंतिम चरण में तमाम पिटे हुए मोहरों के बीच जगन्नाथ मिश्र का सिक्का चल निकला।

चुनावी पराजय के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह ने त्यागपत्र देने की अनुमति आलाकमान से मांगी तथा जगन्नाथ मिश्र ने त्यागपत्र दे दिया। इसके तत्काल बाद जगन्नाथ मिश्र तथा सत्येंद्र नारायण सिंह दिल्ली कूच कर गये। दिल्ली में बिहार को लेकर युद्धस्तर पर परामर्श जारी था। पहले दरबारा सिंह तथा वसंत साठे ने दिल्ली में बिहार के तमाम दिग्गज राजनीतिज्ञों से मंतव्य पूछा। अधिकांश लोग सत्येंद्र नारायण सिंह को हटाये जाने के पक्ष में थे। जगन्नाथ मिश्र का नाम मुख्यमंत्री पद हेतु जोर पकड़ता देख सभी दिग्गज परेशान हो उठे। लिहाजा, यह मुहिम छेड़ी गयी कि फिर से बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाये। दिल्ली में अपने नाम पर प्रबल विरोध देख जगन्नाथ मिश्र ने यह फार्मूला उछाला कि बिहार में यथास्थिति रहने दी जाये। सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने रहें और वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। पर अनायास हालात अनुकूल होते दिखाई दिये। आरके धवन भी जगन्नाथ मिश्र को सत्ता सौंपे जाने के लिए जमकर लॉबी कर रहे थे। आखिरकार फैसला जगन्नात मिश्र के पक्ष में गया। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की सत्ता गंवाने के बाद आलाकमान बिहार में कांग्रेस की सत्ता को हर सूरत में बरकरार रखने को कटिबद्ध था। तस्वीर साफ हो चुकी थी। सत्येंद्र नारायण सिंह को कह दिया गया कि वे पटना जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दें। ५ दिसंबर की दोपहर सत्येंद्र नारायण सिंह सेवा विमान से पटना आये। यों उन्हें लाने के लिए बिहार सरकार का विमान दिल्ली पहुंचा हुआ था। पर इस्तीफे के हुक्म से क्षुब्ध सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार सरकार के विमान से पटना आने को तैयार नहीं हुए। जगन्नाथ मिश्र दिल्ली में ही रुके रहे। जगन्नाथ विरोधी लॉबी अभी भी राजीव गांधी के पास एड़ी चोटी एक किये हुई थी कि जगन्नाथ मिश्र के बजाय बिंदेश्वरी दुबे को ही भेजा जाये। ५ दिसंबर की शाम को सत्येंद्र नारायण सिंह जब पटना में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे, तो उनके बोरिंग रोड स्थित निवास पर एक सुनियोजित ड्रामा हुआ। जब सत्येंद्र नारायण राज्यपाल के यहां जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे कि उनके कुछ समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथ से इस्तीफा छीन लिया। सत्येंद्र-समर्थक नारे लगा रहे थे कि अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसी सूरत में वे सत्येंद्र को इस्तीफा देने देंगे। बहरहाल, सत्येंद्र नारायणं सिंह के निवास पर कुछ देर का यह सुनियोजित रंगारंग कार्यक्रम दिलचस्प रहा।

जगन्नाथ मिश्र ने अपने ४० सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व विधानसभाध्यक्ष शिवचंद्र झा, रामलखन सिंह यादव, रामाश्रय सिंह आदि तमाम धुरंधरों को शामिल किया है। बेशक यह लंबा-चौड़ा मंत्रिमंडल चुनावी मंत्रिमंडल है। हर गुट के लोगों को तरजीह दी गयी है। बिलकुल अंतिम घड़ी में जगन्नाथ मिश्र को मिली यह सत्ता वाकई चुनौतीपूर्ण है। आगामी विधानसभाई चुनाव में अगर वे कांग्रेस को विजयी बनाकर सरकार बनाने की स्थिति में ला देते हैं, तो उनका हाथ फिर जल्दी कोई पकड़ नहीं सकेगा। बिहार राजनीति के एक पुराने दिग्गज 'माया' से कहते भी हैं कि कांग्रेस का हाथ तो बिहार में पिट गया। देखें जगन्नाथ का हाथ क्या कर पाता है। सचमुच जगन्नाथ मिश्र को जिस संकट की घड़ी में सत्ता सौंपी गयी है, उसमें उन्हें 'अपना हाथ जगन्नाथ' का मुहावरा ही सिद्ध करना होगा।

—विकास कुमार झा

बिहार

कांग्रेसी सूपड़ा कैसे साफ हुआ ?

बिहार में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह की गद्दी डा॰ जगन्नाथ मिश्र को मिल गयी है। लेकिन क्या कांग्रेस की हार के लिए अकेले मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार थे ?

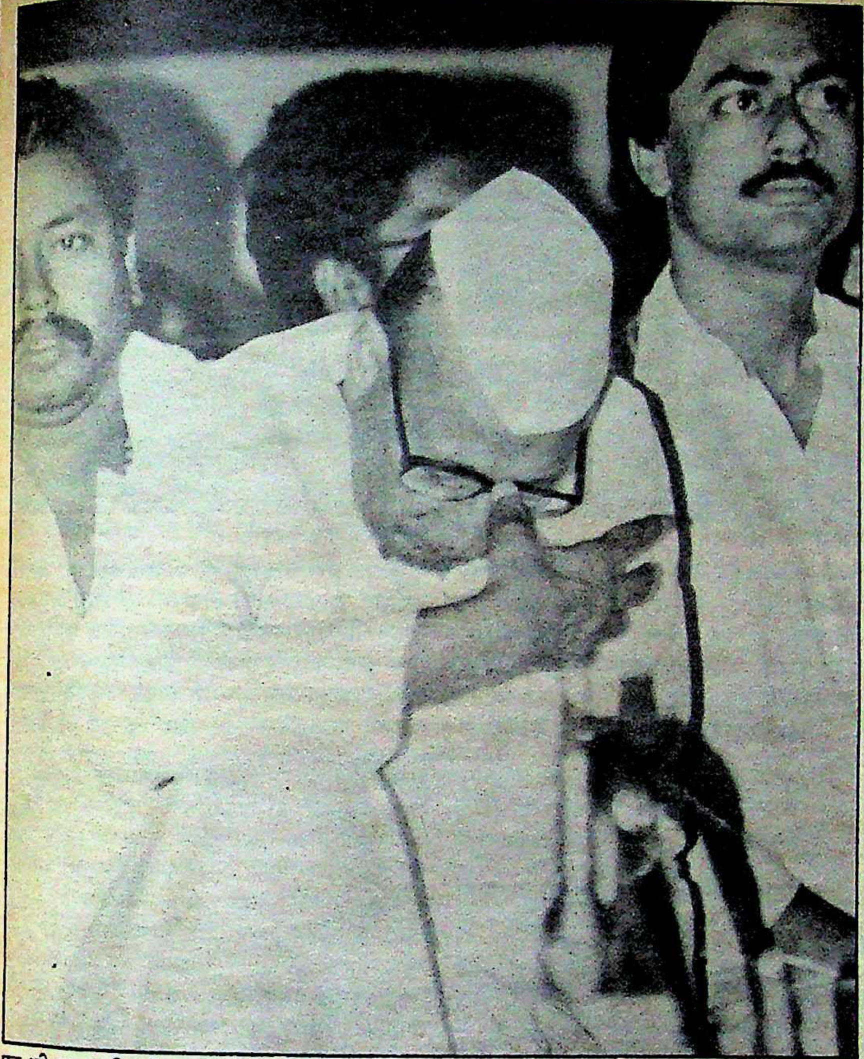

पद भी गया : निवर्तमान मुख्यमंत्री सिंह

"कांग्रेस का चुनाव-चिन्ह है हाथ। हाथ में पांच उंगलियां होती हैं। पर बिहार में कांग्रेस को उंगलियों पर गिनने के लिए पांच सीट भी नहीं मिल सकी।" बिहार से लोकसभाई चुनाव परिणामों के संदर्भ में कांग्रेस के एक पुराने महारथी ने तिक्त होकर यह टिप्पणी 'माया' से की। आखिर बिहार में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हुई, इसको लेकर सबसे नायाब टिप्पणी मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पराजय का एक प्रमुख कारण बीबीसी का धुआंधार दुष्प्रचार भी है। पर कांग्रेस के और तमाम दिग्गज नेता अपनी इज्जत बचाने के लिए इस रेडीमेड उत्तर से लैस थे कि अकेला बिहार ही क्यों, पूरे उत्तर भारत में ही कांग्रेस के खिलाफ यह गुप्त लहर थी। पर इस ठंडी सफाई के नेपथ्य में 'अगर' और 'यदि' जैसे प्रसंग पटना के हर प्रमुख कांग्रेसी किले में बहस के मुद्दे बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी सिन्हा वैशाली में जनता दल की उषा सिंह से परास्त हो गयीं और औरंगाबाद से उनकी पुत्रवधू श्यामा सिंह भी मात खा गयीं। मुख्यमंत्री की अपनी समधिन माधुरी सिंह पूर्णिया में पराजित हो गयीं। एक परिवार में तीन चित्त । सत्येंद्र नारायण सिंह के एक खासुलखास ने मातमी माहौल में 'माया' से कहा, "अगर किशोरीजी को औरंगाबाद से और श्यामाजी को वैशाली से लड़ाया गया होता, तो आज यह दिन न देखना पड़ता।" मुख्यमंत्री के एक खास युवा तुर्क ने इस पर छूटते हुए कहा, "जानते हैं, जब टिकट की घोषणा हुई, तो औरंगाबाद के एक वयोवृद्ध शुभचिंतक ने मुझसे कहा था कि गलती हो गयी। अगर हम लोगों की भाभीजी (किशोरी सिन्हा) औरंगाबाद से लड़तीं और तुम लोगों की भाभीजी (श्यामा सिंह) वैशाली से खड़ी होतीं, तो दोनों की जीत पक्की थी।" इस भाभी-लड़ाओ प्रसंग को बीच में काटते हुए मुख्यमंत्री से संबद्ध एक अधिकारी ने उक्त उत्साही युवा तुर्क को चुप कराते हुए कहा, "ये सब बातें तो अपनी जगह हैं ही, पर दरअसल हुआ यह कि जब हमारे साहब मुख्यमंत्री बन गये, उसके तुरंत बाद मैडम (किशोरी सिन्हा) बीमार हो गयीं। कई महीनों तक वैशाली के लोगों से उनका संपर्क टूटा रहा। हर आदमी बस नौकरी मांगने के लिए ही आता था। सबको नौकरी देना संभव था नहीं। सो बस मैडम के खिलाफ लोग होते चले गये।"

महिला वोट: कांग्रेसी दिग्गज डा॰ जगन्नाथ मिश्र 'माया' से कहते हैं, "कांग्रेस की हार के पीछे कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि भय और आतंक के वातावरण के कारण ज्यादातर महिला मतदाताओं ने वोट नहीं गिराया जो कांग्रेस का पक्का वोट था।" शायद यह भी एक कारण था कि चुनावी जंग में अधिसंख्य महिला उम्मीदवारों को पराभव का सामना करना पड़ा। बेगूसराय से केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णा शाही अपने जनता दल प्रतिद्वंद्वी ललित विजय सिंह से भारी मतों से हारीं। सासाराम से बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री मीरा कुमार जनता दल प्रत्याशी छेदी पासवान से पिछड़ गयीं। बांका में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ चंद्रशेखर सिंह की पत्नी को विश्वनाथ प्रताप सिंह के अपने समधी गिद्दौर के महाराज प्रताप सिंह से हारना पड़ा। वहीं पूर्णिया में मुख्यमंत्री की समधिन माधुरी सिंह को जनता

बाहुबली को मात : गोपालगंज में वीपी राजमंगल मिश्र के साथ

रिकार्ड तोड़ा : पासवान

दल के तसलीमुद्दीन से मुंह की खानी पड़ी। वैशाली में किशोरी सिन्हा भी जनता दल की ही उषा सिंह से पराजित हुई। औरंगाबाद में भी मुख्यमंत्री की पुत्रवधू श्यामा सिंह को जनता दल के रामनरेश सिंह से हारना पड़ा। बलिया में कांग्रेस की चंद्रभानु देवी कम्युनिस्ट प्रत्याशी सूर्यनारायण सिंह से परास्त हुई और मोतिहारी में कांग्रेस की प्रभावती गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राधामोहन सिंह से हार बैठीं। हां, लोहरदगा में कांग्रेस उम्मीदवार केंद्रीय राज्यमंत्री सुमति उरांव को विजयश्री हासिल हुई।

ब्राह्मण-हरिजन वोट : बिहार के चुनावी नतीजों से पता चलता है कि ब्राह्मण तथा हरिजनों का वोट भी कांग्रेस को ठीक से नहीं मिल सका। चुनाव परिणाम बताते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सभी सीटों पर हरिजन मतदाताओं ने कांग्रेस के हरिजन प्रत्याशी के मुकाबले विपक्ष के हरिजन प्रत्याशी को ही पसंद किया। मसलन,

साक्षात्कार : डॉ० जगन्नाथ मिश्र

आम आदमी के गुस्से का फायदा विपक्ष को मिला

माया : ***बिहार में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, इसके पीछे आपकी दृष्टि में क्या वजह हो सकती है?***

मिश्र : एक सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है। संपूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण राजनीति और चुनाव का संप्रदायीकरण है। इतना तो पूरे दावे के साथ मैं अभी भी कहूंगा कि देश के मतदाताओं ने कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के प्रति अपनी अनास्था नहीं दिखायी है। कांग्रेस के प्रति लोग अभी भी पूरी तरह आस्थावान हैं। अगर यह आस्था नहीं होती, तो दक्षिण भारत में जो प्रबल समर्थन मिला है, क्या वह संभव होता? दरअसल, चुनाव के दौरान लगातार संशय और भ्रम की स्थिति का दंड कांग्रेस को भुगतना पड़ा। रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद की अनिश्चितता और उससे उत्पन्न भ्रम के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों कांग्रेस से विमुख हो गये। बिहार में भागलपुर के भीषण दंगे ने स्थिति और खराब कर दी। फिर अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण कार्य के स्थगन से भी प्रभाव पड़ा। इस तरह ऐसी परिस्थिति लगातार बनती चली गयी कि हिंदू और मुस्लिम मतदाता दोनों बिदक गये। पर

एक सिर्फ यही कारण पराजय का नहीं है। लोगों को अपने प्रांतों में स्थानीय शासन से भी घोर निराशा थी। लोगों को यह महसूस हो रहा था कि उनकी समस्या के प्रति स्थानीय प्रशासन में थोड़ी भी संवेदना नहीं है। चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो, सूखा हो, ऐसे संकट के अवसरों पर लोग दुर्दशा झेलते रहे। लिहाजा, अपनी प्रांतीय सरकार के प्रति वर्षों से संचित लोगों का क्रोध बहुत स्वाभाविक रूप से चुनाव परिणाम में जाहिर हुआ। आम आदमी के इसी गुस्से का फायदा विपक्ष को मिला। पर लोग यह महसूस करते हैं कि जैसा भी हो, पर सरकार तो कांग्रेस ही चला सकती है। यह विपक्ष के वश की बात नहीं। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को तो झकझोरा जरूर, पर विपक्ष की क्षमता के प्रति लोगों का अविश्वास ही वह कारण है कि विपक्ष को भी स्पष्ट बहुमत की खुशहाली सीधे-सीधे नसीब नहीं हो सकी।

माया : ***चुनाव परिणाम के बाद आपने बयान भी दिया कि बिहार में प्रशासनिक विफलता के कारण ही कांग्रेस हारी है। क्या सत्येंद्र नारायण सिंह की सरकार आपकी दृष्टि में प्रशासनिक रूप से बिलकुल नाकारा रही?***

मिश्र : चुनावी कुपरिणाम के बाद ही नहीं, बल्कि मैं तो बहुत पहले से इस बात को कहता रहा कि बिहार में सरकार की निरंतर प्रशासनिक विफलता से लोग सुलग रहे हैं। पर मेरी बातों को लोगों ने इस रूप में लिया कि मैं स्वयं सत्ता में आने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। जबकि ऐसी बात दूर-दूर तक नहीं थी। मैं तो इसलिए यह कहता रहा कि हमारा यह प्रदेश बिहार बचा रहे। बिहार की मिट्टी पलीत न हो जाये। पर उस अंधी दौड़ में कोई सुनना नहीं चाहता था, यह सब। लिहाजा, वही हुआ जो आज सामने है। पूरे प्रदेश में विकास योजनाएं वर्षों से ठप रहीं। प्रांतीय शासन अगर इस पर ध्यान देता, तो आज यह स्थिति नहीं होती। प्रशासनिक विफलता की यह स्थिति अभी चरम पर जरूर आ गयी थी। पर यह चरम की स्थिति अचानक नहीं आयी। पिछले वर्षों में अराजकता को

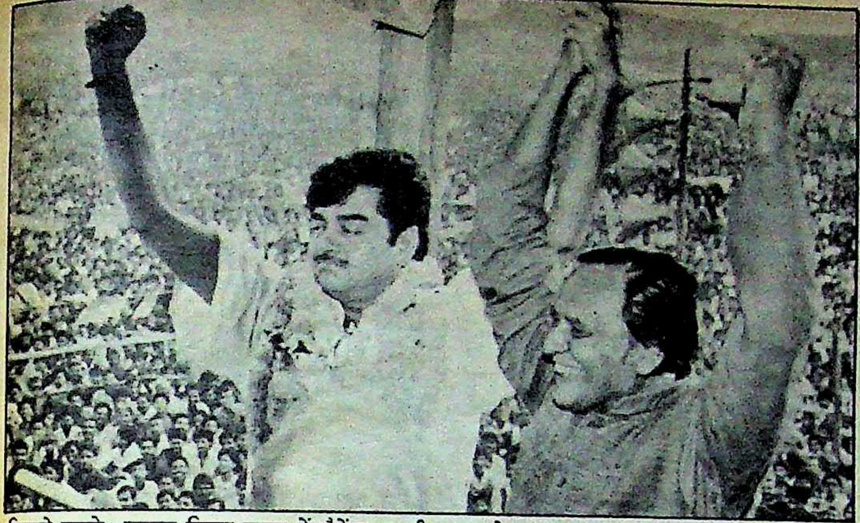

सितारे चमके : शत्रुघ्न सिन्हा पटना में शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव के साथ

बगहा सुरक्षित क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भोला राउत जनता दल के अपने प्रतिद्वंद्वी महेंद्र बैठा से बुरी तरह हारे। हाजीपुर सुरक्षित सीट से जनता दल के उम्मीदवार रामविलास पासवान ने कांग्रेस के महावीर पासवान को ऐसे-वैसे नहीं, बल्कि रिकार्ड तोड़ मतों से हराया। हाजीपुर में रामविलास ने १९७७ के चुनाव का अपना बनाया रिकार्ड खुद तोड़ा। १९७७ में रामविलास जब ४ लाख २४ हजार ५४५ वोट से जीते थे, तो उनका नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ था। पर इस बार रामविलास उससे भी ज्यादा मतों से जीते। उन्होंने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वी को ४ लाख ९८ हजार ३६६ मतों से हराया। रोसड़ा सुरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस के रामभगत पासवान की भी यही गति हुई। रामभगत जनता दल के दसई चौधरी से पिट गये। सासाराम में बाबूजी की बेटी मीरा कुमार हार गयीं। नवादा सुरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस के कुंवर राम सीपीएम के प्रेम प्रदीप से बेतरह मात खा गये। गया सुरक्षित सीट में कांग्रेस प्रत्याशी रामस्वरूप राम भाजपा के ईश्वर चौधरी से हार गये। पलामू सुरक्षित सीट से कांग्रेस की कमला कुमारी को परास्त होना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं कि हरिजन मतदाता भी एकमुश्त कांग्रेस से चुपचाप खिसक लिये। ब्राह्मण वोट भी कांग्रेस को क्या मिला, इसका जायजा गोपालगंज सीट के परिणाम से लिया जा सकता है। कांग्रेस ने इस बार यहां से चर्चित बाहुबली काली पांडेय को अपना उम्मीदवार बनाया था। वही काली पांडेय जो १९८४ के कांग्रेस लहर में गोपालगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे। विपक्षी सांसदों ने जब सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया, तो ऐन उसी समय काली पांडेय कांग्रेस में शामिल हो गये थे। काली पांडेय के विरुद्ध वयोवृद्ध नेता राजमंगल मिश्र को इस बार गोपालगंज में जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था। राजमंगल मिश्र ने जबर्दस्त मतों से काली पांडेय को हरा दिया।

ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण : स्पष्ट है कि कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी के मुकाबले जहां विपक्ष ने भी अपना ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, वहां ब्राह्मण मतदाताओं ने भी विपक्ष के ही ब्राह्मण प्रत्याशी को प्राथमिकता दी। हजारीबाग में भी यही हुआ। कांग्रेस के दामोदर पांडेय भाजपा के यदुनाथ पांडेय से हार गये। इतना ही नहीं, विपक्ष से खड़े होने के कारण ही कई ब्राह्मण उम्मीदवार जीत का मुंह भी देख सके। मधुबनी में जहां कम्युनिस्ट उम्मीदवार भोगेंद्र झा ने कांग्रेस के हन्नान अंसारी को हराया, वहीं सीवान में भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन तिवारी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को बुरी तरह परास्त कर दिया। एक तरफ जहां विपक्षी रथ पर आरूढ़ ये ब्राह्मण उम्मीदवार विजयी रहे, वहीं ब्राह्मणों के गढ़ माने जाने वाले दरभंगा संसदीय सीट से जनता दल के उम्मीदवार डा० शकीलुर्रहमान ने मैथिल राजनीति के स्वयंभू महंत नागेंद्र झा को बुरी तरह पराजित किया। दरभंगा में मैथिल युवकों ने भी शकीलुर्रहमान को वोट दिया। शकील को दरभंगा में नागेंद्र झा की अतिविवादास्पद छवि का पूरा फायदा मिला। बेतिया की भी गिनती ब्राह्मण सीट के रूप में होती रही है। पर यहां से बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके स्व० केदार पांडेय के पुत्र डा० मनोज पांडेय इस बार हार गये। झंझारपुर क्षेत्र को डा० जगन्नाथ मिश्र का किला माना जाता रहा है। पर यहां से कांग्रेस के डा० गौरीशंकर राजहंस को मुंह की खानी पड़ी। सहरसा में कांग्रेस के चंद्रकिशोर पाठक की भी ऐसी ही दुर्गति हुई। और-तो-और

रफ्तार मिलती गयी जो चुनाव तक काफी तेज हो गयी थी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार के आम लोग अभी भी कांग्रेस के प्रति आस्थावान हैं कि तमाम बातों के बावजूद कांग्रेस ही इस सूबे की स्थिति ठीक कर सकती है।

माया : ***लोकसभा चुनाव में तपेश्वर सिंह जैसे विवादास्पद छवि के लोगों को टिकट दिया जाना भी कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण माना जा रहा है?***

मिश्र : इस चुनाव में मूल्य और आदर्श पर ही सभी बातें आधारित थीं, ऐसा नहीं। अंतिम क्षण में कांग्रेस से निकलकर जनता दल में गये धनराज सिंह जैसे लोगों को जनता दल ने भी टिकट दिया और ऐसे लोग जीते भी।

माया : ***क्या आपको विश्वास है कि शीघ्र ही होनेवाले विधानसभाई चुनाव में कांग्रेस अपनी स्थिति यहां सुधार लेगी?***

मिश्र : मुझे तो विश्वास है। पर ऐसा तभी होगा, जब लोगों को हम पूरी तरह यकीन दिला देंगे कि अब पहले जैसी शैली को हम नहीं दुहरायेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभाई चुनाव में यहां कांग्रेस को प्रबल बहुमत मिलेगा।

माया : ***चुनाव में भारी पराजय के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि राजीव गांधी का नेतृत्व अस्वीकृत हो चुका है? क्या कांग्रेस में राजीव गांधी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठने के आसार आपको दिखाई देते हैं?***

मिश्र : चुनाव में एक बार पराजय का अर्थ यह नहीं कि कोई नेतृत्व अस्वीकृत हो जाता है। राजीव गांधी का नेतृत्व कतई अस्वीकृत नहीं हुआ है। कांग्रेस में राजीव गांधी के विरुद्ध आवाज उठने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वे हमारे नेता हैं और रहेंगे। दूसरों की बात मैं क्या कह सकता हूं, पर अपनी बात मैं जरूर कहूंगा कि पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति राजीव गांधी के पीछे रह जायेगा, तो वह मैं ही होऊंगा।

माया : ***पर गुजरे वर्षों में जिस शैली में राजीव गांधी ने कांग्रेस को नेतृत्व दिया, क्या अब भी उसी शैली में नेतृत्व देकर राजीव कांग्रेस को उबार सकेंगे?***

मिश्र : उन्हें और अधिक राजनीतिक बनना पड़ेगा। पार्टी को और अधिक जनाधारित तथा लोकतांत्रिक छवि से पूरी तरह लैस करने की जरूरत है।

माया : ***आप बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष बनाये गये और पार्टी की प्रांतीय कमेटी बनने ही नहीं दी गयी, क्या चुनाव में इसका भी कुप्रभाव पड़ा?***

मिश्र : अवश्य पड़ा। पर अब उन शिकवे-शिकायतों का समय नहीं। अब नये सिरे से पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है।

—विकास कुमार झा

> **पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति राजीव गांधी के पीछे रह जायेगा, तो वह मैं ही होऊंगा**

बिहार में माफिया किलर मुख्यमंत्री के रूप में मशहूर भागवत झा आजाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र भागलपुर में रिकार्ड मतों से हारे। वे मात्र ३५५ मत के फर्क से अपनी जमानत किसी तरह बचा पाये।

मुस्लिम वोट: मुस्लिम वोटों पर इस बार यों भी कांग्रेस को विश्वास नहीं था। कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों में एक मात्र किशनगंज से प्रख्यात पत्रकार एमजे अकबर जीत सके। एक और बात सामने आयी कि कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों को भाजपा प्रत्याशियों ने हराया। सीवान में भाजपा के जनार्दन तिवारी ने अब्दुल गफूर को तो हराया ही, गोड्डा में भी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवार से हारे। गिरिडीह में भी भाजपा के रामदास सिंह ने कांग्रेस के सरफराज अहमद को हराया। ऐन चुनाव के दो दिन पहले हाजी मस्तान ने बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के नाम जो अपील भेजी, उसने काफी रंग लाया। इस अपील में हाजी मस्तान ने मुस्लिम मतदाताओं से गुजारिश की थी कि शपथपूर्वक वे इस चुनाव में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ वोट दें। हाजी मस्तान ने अपील में कहा था कि जिस सत्येंद्र नारायण सिंह की हुकूमत में बिहार में मुसलमान काटे जाते रहे, उन्हें तारिक अनवर जैसे कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने रफीक-ए-उर्दू का खिताब दिया। ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाना चाहिए। कटिहार में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अनवर को मुसलमानों का भी वोट पूरा नहीं मिल सका और वे जनता दल के प्रत्याशी युवराज से काफी मतों से हारे। चुनाव के पूर्व यह लगभग तय माना जा रहा था कि मुस्लिम मतदाता कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देंगे। इसके पीछे तर्क यह था कि मुस्लिम कांग्रेस को तो वोट देंगे नहीं और भाजपा से चुनावी तालमेल रखने के कारण जनता दल से भी उनको परहेज होगा। इसलिए एक मात्र कम्युनिस्ट पार्टी ही बचती है जिसे मुस्लिम वोट देंगे। पर यह अटकल भी गलत साबित होकर रह गयी। अगर वाकई ऐसा होता, तो पटना संसदीय सीट से कम्युनिस्ट प्रत्याशी रामनाथ यादव हारते नहीं। पटना से कांग्रेस के डा० सीपी ठाकुर को भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रो० शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने हराया। रामनाथ यादव इस गणित की खुशफहमी में रह गये कि उन्हें अपनी जाति का यादव वोट मिलेगा ही और मुसलमानों का भी एकमुश्त वोट मिल जायेगा। पर चुनावी नतीजे ने रामनाथ यादव के इस गणित को गलत ठहरा दिया। पटना में यों भाजपा की कोई हवा नहीं थी। सच तो यह था कि भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र नाथ का चुनाव अभियान भी शुरू में बेहद ढिलमिलाया हुआ था। पर चुनाव के एकदम अंतिम चरण में अटलबिहारी वाजपेयी की पटना के गांधी मैदान में हुई विशाल जनसभा ने पांसा पलट दिया। उस दिन जनसभा में अटलबिहारी वाजपेयी के साथ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के लिए मतदाताओं से अपील करने आये हुए थे। अटलजी ने मंच पर शत्रुघ्न से चुटकी भी ली और प्रकारांतर से जताया कि गांधी मैदान की यह अपार भीड़ अभिनेता को नहीं नेता को सुनने के लिए जुटी है। अटलजी ने हंसते हुए कहा, ''अभी बिहारी बाबू शत्रुघ्नजी को लग रहा होगा कि उन्हीं को देखने यह भीड उमड़ आयी है, पर भाई यहां एक अटल 'बिहारी' भी मौजूद है।''

पराजित: बांयें से, तारिक अनवर, काली पांडेय, किशोरी सिन्हा

सीपीआई को निराशा: पटना की भांति मुंगेर में भी कम्युनिस्ट उम्मीदवार ब्रह्मानंद मंडल को यकीन था कि उन्हें मुस्लिम मत जरूर मिलेगा। पर मुंगेर में अधिसंख्य मुस्लिम मत जनता दल के धनराज सिंह को मिला। मुंगेर में धनराज सिंह ने कांग्रेस के डीपी यादव को हराया। चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति लगभग जस-की-तस रही। नालंदा, मोतिहारी, जमशेदपुर आदि सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी को जीत की पूरी आशा थी। पर कम्युनिस्ट पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। केवल बलिया और जहानाबाद की सीट पाकर कम्युनिस्ट पार्टी को संतोष करना पड़ा। यों अन्य वामपंथी दलों ने बिहार से संसद में अपना खाता खोला। सीपीएम के प्रेम प्रदीप जहां नवादा से जीते, वहीं इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने आरा सीट हासिल की। यहां से फ्रंट के प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद ने कांग्रेसी दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री बलिराम भगत को हराया। यों फ्रंट ने जहानाबाद से अपने प्रांतीय अध्यक्ष कृष्णदेव यादव को खड़ा किया था, पर वे हार गये। विक्रमगंज में सहकारी कुबेर तपेश्वर सिंह के खिलाफ फ्रंट ने बच्चन सिंह को उतारा था। बच्चन सिंह को ८७,०८५ वोट मिले। तपेश्वर तो यहां संघर्ष में तीसरे नंबर पर थे। जनता दल के रामप्रसाद कुशवाहा ने तपेश्वर की सीट से जीत हासिल की। वामपंथी तेवर के संगठन 'मार्क्सवादी कोआर्डिनेशन' के प्रत्याशी और धनबाद में मजदूरों के मसीहा एके राय ने माफिया की राजधानी के रूप में मशहूर धनबाद पर जीत का झंडा लहराया। इन परिणामों से जाहिर है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त मतदाताओं ने आईपीएफ, सीपीएम तथा मार्क्सवादी कोआर्डिनेशन जैसे संगठन को भी थोड़ी तरजीह दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अच्छी सीटें मिलीं। दुमका से मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शीबू सोरेन, जमशेदपुर से मुक्तिमोर्चा के महासचिव शैलेंद्र महतो तथा राजमहल से मोर्चा के साइमन मरांडी जीते। आदिवासी अंचल में कांग्रेस की भी थोड़ी टेक रह गयी। लोहरदगा से कांग्रेस की सुमति उरांव जीतीं और सिंहभूम से कांग्रेस के बागुन सुंब्रई जीते। खूंटी से करिया मुंडा को विजयी बना कर आदिवासियों ने एक सीट भाजपा को भी दी।

बाहुबलियों की उपेक्षा: माफिया-छविधारियों तथा बाहुबलियों को भी मतदाताओं ने दूनी ताकत से खारिज किया। तपेश्वर सिंह जैसों की हार इसी तरफ इशारा करती है। दरभंगा में नागेंद्र झा तथा रांची में शिव प्रसाद साहु ने जीत के लिए बेहिसाब रुपए बहाये। पर मतदाताओं ने उन्हें भी सबक दिया कि पैसे की राजनीति के दिन अब लद गये।

दंगा, दादागिरी और दहशत के बीच बिहार में चुनाव हुआ। अनगिनत लोग मौत के घाट उतारे गये। आरा में तो एक निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिंह की मतदान के दिन हत्या कर दी गयी। आरा से ही तकरीबन ६५ किलोमीटर दूर तरारी थाने के दनवार बिहटा गांव के पांच लोग चुनावी चक्कर में मौत के घाट उतारे गये। फिर हत्या की प्रतिक्रिया में तुरंत दस-बारह हत्याएं और हुईं। बिहार में चुनाव बगैर बूथ कब्जा के संपन्न हो, यह असंभव है। बिहार सरकार के मंत्री रघुनाथ पांडेय, कृपानाथ पाठक तथा संजीव टोनी पर आरोप लगा कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी को विजयी बनाने के लिए वैशाली में बूथ लूटते फिर रहे थे। सहकारिता राज्यमंत्री दिलीप कुमार सिन्हा के खिलाफ भागलपुर क्षेत्र में बूथ लूटने के आरोप में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी भी दर्ज करायी। बिहार के मतदाताओं ने यह भी दोटूक जता दिया कि बूथ कब्जा कर एमपी, एमएलए बनने के दिन गये। बहरहाल, संसदीय चुनाव की समाप्ति के साथ ही बिहार में शीघ्र संभावित विधानसभाई चुनाव को लेकर अटकलें तेज हैं कि मतदाता बिहार विधानसभा में किसको कैसा झटका देनेवाले हैं? **—विकास कुमार झा**

मध्य प्रदेश

सीधी टक्कर का लाभ भाजपा को

जो कांग्रेस-इ '८४ के आम चुनाव में मप्र में लोकसभा की कुल चालीसों सीटें मार ले गयी थी, वह इस बार बमुश्किल मात्र ८ स्थान पा सकी। यह इंका विरोधी हवा की नहीं, चुनावी समीकरण की देन थी। क्या था वह समीकरण?

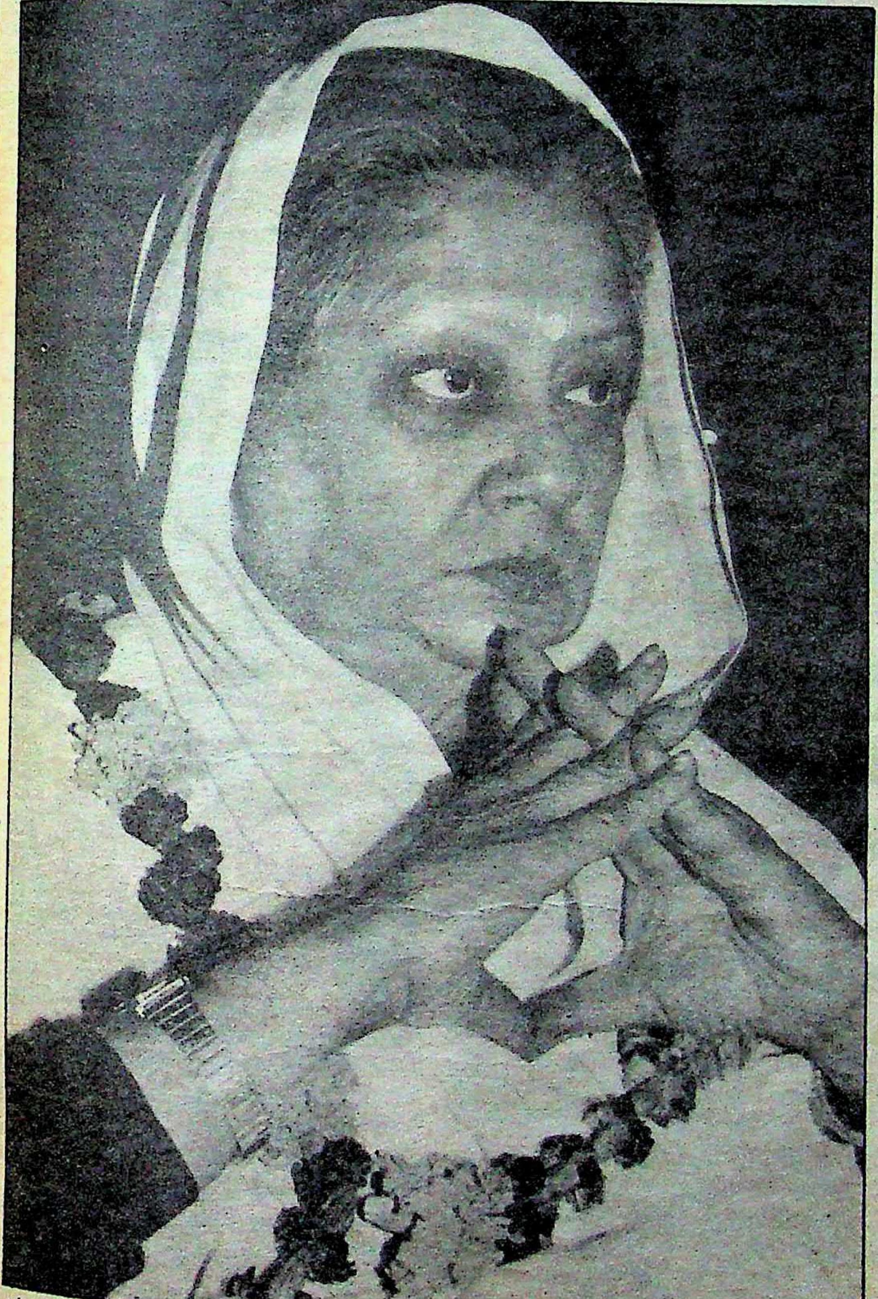

संघर्ष की सफलता: राजमाता विजयराजे सिंधिया

और अनहोनी होकर रही। मतदान पूर्व एक पखवारे तक मप्र के सघन दौरे ने यह उजागर कर दिया था कि प्रदेश में सत्तादल के लिए उलटी हवा बह रही है। बहुतेरे उम्मीदवारों को इसका आभास भी हो गया था, लेकिन कुछ थे कि अतीत के नतीजों के भरोसे स्वयं को झूठी तसल्ली दे रहे थे। खंडवा में सर्किट हाउस में कांग्रेसी प्रत्याशी कालीचरण शकरगाय से अकस्मात मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, "मैं जीतूं या हारूं, मगर हरसूद के डुबान में आ रहे लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां रिफाइनरी खुले।" हालांकि शकरगाय यह नहीं बता सके कि उन्होंने तेल शोधक की स्थापना और डुबान के लोगों की भलाई के लिए कितना जतन किया है। रास्ते में तांगाचालक से और चाय की गुमटी पर तमाम लोगों से बातें हुई, तो सबने कहा कि उन्होंने बरसों से शकरगाय को नहीं देखा।

राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के खिलाफ सघन प्रचार कर वीरेंद्र कुमार सखलेचा इंदौर लौटे, तो उनका चेहरा खिला हुआ था। इंदौर में सट्टा बाजार पहले से गरम था। सट्टा बाजार का रुख बताता था कि कांग्रेस की हालत पतली है। सभाओं को संबोधित कर लौटे सखलेचा से रात बारह बजे के बाद भेंट हुई, तो उन्होंने कहा हम ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह से फोन पर बात हुई थी। उनका कहना था—"बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन राजगढ़ में मैं जीत रहा हूं।" उनके वाक्य का समापन चिरपरिचित ठहाके में हुआ और आशंकाएं इसी ठहाके में खो गयीं।

जांजगीर में जब चारों ओर दिलीप सिंह जूदेव के चुनाव प्रचार की दुंदुभि बज रही थी, इंका प्रत्याशी प्रभात मिश्र जीपें, पैसे और पोस्टर लेने स्वयं भोपाल गये हुए थे। रायगढ़ पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि इंका प्रत्याशी कुमारी पुष्पा देवी पांवों पर बंधा प्लास्टर खुलवाने दिल्ली गयी हैं। रायपुर में कांग्रेसी प्रचारकों ने रोना रोया कि अधिकांश कार्यकर्ता केयूर भूषण की पुनः उम्मीदवारी से नाराज हो महासमुंद चले गये हैं।

इंदौर से खरगोन जाते हुए भीकनगांव में जामा मस्जिद के बाहर इमाम हाफिज अब्दुल हादी ने बातचीत में कहा, "मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते आये हैं, भले ही वो किसी गधे पर ही फूल क्यों न डाल दें, मगर इस बार कहना मुश्किल है। चारों ओर भाजपा का जोर नजर आता है।" इमाम ने शिकायत की कि वायदे के बावजूद न तो गांव में उर्दू स्कूल खुला और न ही कब्रिस्तान के लिए जमीन मिली। चलते-चलते इमाम ने कहा कि अगर खरगोन से मुस्लिम लीग का उम्मीदवार होता, तो वे लोग उसे जरूर वोट देते। कांग्रेस में

उन्हें अब पहले सी आस्था नहीं रही।

मध्यभारत और निमाड़ में गांवों में दीवारों पर नारे लिखे दिखे: 'राम चाहिए या राजीव चाहिए?' इंदौर में बंबई बाजार और आस पास् के इलाकों में जगह-जगह अंकित था: "अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आनेवाला।" सांप्रदायिक हिंसा के बाद बाला बेग को जेल में रासुका के तहत डाल दिया गया था, मगर उनका प्रचार बहुत जोरशोर से चल रहा था। इसके विपरीत कांग्रेसी दिग्गज प्रकाशचंद सेठी से भेंट के लिए रात करीब पौने आठ बजे रूबरू संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा, "बेहतर होगा कि आप कल सवेरे आयें। मैं नहा धोकर सोने जा रहा हूं।"

ऐसे में नतीजा और क्या होना था? एक ओर भिंड-मुरैना से लेकर सरगुजा तक और दूसरी ओर निमाड़ से लेकर रींवा तक चुनाव मैदान में इंका खेत रही। दिग्गज और महारथी नेताओं में केवल माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस की लाज रखी। "आप मुझे पांच मिनट दीजिए, मैं आपको पांच साल दूंगा" की उनकी अपीलों का असर हुआ। पिछोर, डबरा, गिर्द, ग्वालियर, मुरार की सभाओं में उन्होंने कहा, "मैं कोई वजनदार या बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं इसी मिट्टी का पुत्र हूं और आपसे हमारा पीढ़ियों का अंतरंग और गाढ़ा रिश्ता है। आप मुझे बल दीजिए, ताकि मैं आगे भी उसका उपयोग आपके हित में कर सकूं।" ये बातें लोगों की समझ में आयीं और विपक्षी लहर के बावजूद सिंधिया करीब डेढ़ लाख मतों से जीते। अपने नाम और काम के बल पर सिंधिया स्वयं तो जीते, किंतु उनका प्रभामंडल मप्र, विशेषकर मध्यभारत में कांग्रेस की नैया को डूबने से नहीं बचा सका। तेंदू पत्ता नीति से लेकर 'आपकी सरकार, आपके द्वार' तक के सारे उपक्रम कांग्रेस को चुनावी वैतरणी पार कराने में विफल रहे। विदिशा में भाजपा के नेता सरदार गुरचरण सिंह की कही बात सही निकली कि 'हमारे लिए तो सब तरफ बेर बिछे हैं। अब ये हमारी खूबी है कि हम कितने बेर (वोट) बटोर पाते हैं?'

माधवराव सिंधिया

अपने नाम और काम के बल पर सिंधिया स्वयं तो जीते, किंतु उनका प्रभामंडल मप्र, विशेषकर मध्यभारत में कांग्रेस की नैया को डूबने से नहीं बचा सका।

राजधानी : नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस इस बार बेरों को दूसरों की चादरों पर झरने से रोक नहीं सकी। अतीत से सबक न लेना उसे भारी पड़ा। भोपाल में गत तीन दशकों से परंपरा है कि यहां के मतदाता हर दशक के अंत में विपक्ष को विजयी बनाते हैं। सन् ६७ में जनसंघ के जगन्नाथराव जोशी ने मैमूना सुल्तान को और सन ७७ में आरिफ बेग ने डा० शंकरदयाल शर्मा को हराया था। इस बार बसपा के अब्दुल रऊफ जहां केएन प्रधान की हार का बायस बने, वहीं सन् ६७ में उनके भाई अब्दुल अहद खां ने मैमूना की

क्या कहते हैं वोरा और पटवा?

"हार का दोष भितरघात या सेबोटाज को नहीं दिया जा सकता। हां, कुछ स्थानों पर सेबोटाज जरूर हुआ है, जिसकी शिकायतें पर्यविक्षकों को मिली हैं। कांग्रेस को त्रिकोणी संघर्ष का कहीं कोई लाभ नहीं मिला। बागी उम्मीदवारों और बसपा ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई। भाजपा की जीत धार्मिक और सांप्रदायिक' भावनाओं को उभाड़ने के कारण हुई। वैसे मप्र ही क्यों, सत्ता दल से समूचे उत्तर भारत में नाराजगी जाहिर हुई है। यह कहना सही नहीं है कि कांग्रेस ने जातीयता का सहारा लिया। मेरे खयाल में जिस किसी कांग्रेसी ने जातीय भावनाओं को उभारा है, उसने पार्टी से गद्दारी की है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग आलाकमान को सबक सिखाना चाहते हैं, वे पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं, भले ही वे कितने भी बड़े क्यों न हों। पार्टी की आड़ में स्वयं का वर्चस्व स्थापित करनेवाले नेताओं को जनता पहचानती है। यह कहना गलत है कि तेंदू पत्ता नीति से लोग नाराज हुए। बीड़ी के दाम दोगुने जरूर बढ़े हैं, किंतु मंहगाई इस बार चुनावी मुद्दा नहीं थी। भाजपा ने सांप्रदायिकता भड़काकर वोट बटोरे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नतीजों से भाजपा के हौसले बढ़े हैं। किंतु कांग्रेस अभी भी मिलजुलकर इसका सामना करने में सक्षम है।"

—मोतीलाल वोरा

"जनता से सतत संपर्क व उसकी समस्याओं के लिए सतत संघर्ष का लाभ चुनावों में भाजपा को मिला। जनता में भाजपा के प्रति उसके विवादों से मुक्त होने के कारण सात्विक आकर्षण बढ़ा है। दूसरे युवा मतदाताओं ने हमारा अपेक्षाओं से अधिक साथ दिया। जनता इंका के कुशासन से मुक्ति चाहती थी। सरकार ने बहुसंख्यकों की भावनाओं को लगातार आघात पहुंचाया है। राम जन्मभूमि के मामले में केवल भाजपा ने ही खरी नीति और खरा रवैया अपनाया। राम इस देश के आदर्श व पितृ पुरुष हैं। वे इस देश के सभी संप्रदायों के लोगों के पुरखे हैं। जो इस तथ्य से इनकार करता है, वह अपने पिता को पिता मानने से इनकार करता है।"

—सुंदरलाल पटवा
मप्र भाजपा अध्यक्ष

पराजय का पथ प्रशस्त किया था। रऊफ को ६७८८६ मत मिले। और-तो-और, उन्हें भोपाल उत्तर में इंका और भाजपा दोनों से ज्यादा वोट मिले, जहां से वोरा सरकार में मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी चुने गये थे। इसी प्रकार पूर्व मंत्री और अर्जुन गुट के विधायक हसनात सिद्दीकी के क्षेत्र भोपाल दक्षिण से भाजपा को २५ हजार की बढ़त मिलना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है।

कांग्रेस-इ की मप्र में चतुर्दिक पराजय में सरकारी कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभायी। कर्मचारी नेता नारायणप्रसाद शर्मा ने तो केएन प्रधान और रामेश्वर नीखरा को हराने का खुलेआम फतवा दे दिया था। करीब पौने चार लाख सरकारी कर्मचारियों का झुकाव इस दफा निश्चित ही कांग्रेस विरोधी रहा। कर्मचारी संघों के विवाद में प्रधान और नीखरा का हाथ डालना कांग्रेस के लिए मंहगा सौदा रहा।

राजघराने: सिंधिया घराने के तीन सदस्यों की प्रभावशाली विजय को छोड़ दें, तो नतीजों से स्पष्ट है कि राजघरानों का प्रभाव

विद्याचरण शुक्ल

नतीजों की एक और
अनहोनी यह है कि वीसी केवल
१२८९४ मतों से जीते,
जबकि कौशिक ने चंद्राकर को
१ लाख १० हजार मतों
से पटकनी दी।

कांग्रेस पर कहर

मप्र में इस बार मालवी मुहावरे में कहें, तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। जैसा कि 'माया' का अनुमान था, कांग्रेस का चुनावी-घोड़ा कई ठौर रोका गया और पिछली बार सभी ४० सीटें जीतनेवाली इंका केवल आठ सीटें जीत सकी। जद के तीन प्रत्याशी—वीसी शुक्ल (महासमुंद), पुरुषोत्तम कौशिक (दुर्ग) और यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) विजयी रहे। भाजपा ने पहली बार अपनी अपेक्षा से अधिक २७ सीटों पर झंडा लहराया और सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए बालाघाट से जुझारु तेवर के निर्दलीय (जद से निष्कासित) कमल मुंजारे ने जद के केडी देशमुख को करीब १० हजार मतों से हराया। बालाघाट में इंका सांसद नंदकिशोर शर्मा तीसरे स्थान पर पिछड़ गये। भाजपा के विजयी २७ प्रत्याशियों में सिवनी से जीते, प्रदेश में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी प्रह्लाद सिंह पटेल वस्तुत: बागी भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्हें भाजपा ने पार्टी से तब निकाला जब उन्हें कमल चिह्न आवंटित हो चुका था। २७ वर्षीय प्रह्लाद ने सन् '७७ में समूचे उत्तर भारत में विजयी इकलौते प्रत्याशी गार्गीशंकर मिश्र को हराया।

'माया' द्वारा व्यक्त 'अनहोनी के आसार' चुनाव में खरे उतरे। करीब डेढ़ लाख वोटों से जीतकर माधवराव सिंधिया ने यह रेखांकित कर दिया कि तमाम तिकड़मों के बावजूद भाजपा और पार्टी के भीतर उनके विरोधी उनका जनाधार सरकाने में विफल रहे हैं। महेंद्र सिंह, डालचंद कर्नल मुश्तान, प्रतापभानु शर्मा, सेठी, एसएन पवार, बालकवि बैरागी की सर्वाधिक मतों से हार दर्शाती है कि जनमानस कांग्रेस के विरुद्ध था। आलम यह था कि कांग्रेसी दुर्ग छिंदवाड़ा में कमलनाथ जैसा जागरूक सांसद मेहनत-मशक्कत के बाद केवल ४० हजार मतों से जीत सका। यहां पूर्व मंत्री जद के माधवलाल दुबे ने नाथ को कड़ी लगा दी। नतीजों की एक और अनहोनी यह है कि वीसी केवल १२८९४ मतों से जीते, जबकि कौशिक ने चंद्राकर को १ लाख १० हजार मतों से पटकनी दी।

सचाई यह है कि विपक्ष, विशेष कर भाजपा के पक्ष में लहर, जो कांग्रेस पर कहर बनकर टूटी, एक दिन में अथवा अकस्मात नहीं बनी। 'माया' संवाददाता ने प्रदेश के ओर-छोर दौरों में पाया कि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि प्रकरण ने हिंदू मतदाताओं को गहरे तक आलोड़ित किया है। गांव-गांव में राम शिला-पूजन ने सामान्य जनों की धार्मिक भावनाएं उभाड़कर उन्हें सत्तादल से विमुख किया। रतलाम, धार, महू, खरगौन, इंदौर आदि स्थानों पर दंगों ने आहत भावनाओं को और भड़काया। दोनों हाथों में लड्डू रखने के फेर में कांग्रेस ने हिंदुओं और मुस्लिमों—दोनों का समर्थन खोया। इंदौर में बालाबेग और भोपाल में रऊफ मियां ने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक मतों पर हाथ साफ किया। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही। बसपा के डा० प्रीतम चौधरी ने मुरैना में ६६ हजार, टीआर खुंटे ने जांजगीर में ६२ हजार, राजू राजेश जायसवाल ने जबलपुर में १६ हजार से अधिक वोट बटोरे। इसी प्रकार दूरदर्शी पार्टी के भरत कुमार ने राजापुर में २१ हजार और खजुराहो में महेश कुमार ने २४ हजार से अधिक मत बटोरे।

प्रचार अभियान में कांग्रेस का आंतरिक कलह खुलकर रंग लाया। ग्वालियर में सिंधिया को राजपूत वोटों से वंचित करने की पुरजोर कोशिश हुई। रायपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता केजूर भूषण का प्रचार मझधार में छोड़कर महासमुंद चले गये। ऐसे ही इंदौर, ग्वा शिवपुरी-३ के बहुतेरे जन राजगढ़ चले गये। बैतूल में पुराने कांग्रेसियों ने (बागी) राधाकृष्ण गर्ग की कमान संभाली। शिवेंद्र, प्रतापभानु, नीखरा को पार्टी के अधिकांश विधायकों का मनचीता समर्थन-सहयोग नहीं मिला और चुनाव में जातीय भावनाएं भी भड़कायी गयीं। होशंगाबाद में सरदार सरताज सिंह के खिलाफ अवांछित प्रचार हुआ और सतना में ठाकुरों के दादा सुखेंद्र के पक्ष में होने का हवाला देकर ब्राह्मणों को इंका के पक्ष में एकजुट करने की तगड़ी कोशिशें भी हुईं।

कहना न होगा कि कांग्रेस के ये सभी दांव उलटे पड़े। इंदौर में मजाक में जुमला चल पड़ा कि सेठी बुढ़ापे में पंचमकारों—महिला, महंगाई, मुस्लिम, महाजन खैरया और महाराष्ट्रियन-से घिर गये हैं। पांच मकारों में से प्रारंभिक तीन ने इंदौर में ही नहीं और जगहों पर भी गुल खिलाया। तेंदूपत्ता नीति कितनी भी नेकनीयती से क्यों न बनी हो, बीड़ी के कट्टों के दामों में दोगुनी वृद्धि ने लाखों-करोड़ों उपभोक्ताओं को क्षुब्ध किया। कांग्रेस का हमेशा साथ देनेवाली समृद्ध बीड़ी-लाबी अपवादों को छोड़ इस दफा विपक्ष के साथ रही। दिल्ली-भोपाल से 'फंड' न मिलने की शिकायत कांग्रेसी उम्मीदवारों ने हर कहीं की। रही सही कसर कांग्रेस के अनात्मीय और वितृष्णा उपजानेवाले भारी भरकम विज्ञापनों ने पूरी कर दी। नतीजा यह हुआ कि नतीजों ने जहां कांग्रेसियों का हौसला पस्त किया, वहीं भाजपा के सबसे बड़े—प्रांत में सरकार बनाने के—सपने में नये चटख रंग भर दिये।

—सुधीर

छीजा है। पूर्व मंत्रियों श्रीनिवास तिवारी और कृष्णपाल सिंह ने तो 'माया' से बातचीत में इस पर दुःख भी व्यक्त किया कि कांग्रेस अभी तक राजघरानों के मोह से उबर नहीं सकी है। महेंद्र सिंह (कालूखेड़ा) को इस बात का किंचित संतोष हो सकता है कि वे लहर में राजमाता सिंधिया जैसी हस्ती से परास्त हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह (राघोगढ़), किशन सिंह (दतिया), कुमारी पुष्पा सिंह (रायगढ़), श्रीमती प्रवीण कुमारी (रीवा), शिवेंद्र बहादुर सिंह (राजनांदगांव) की करारी हार उनके छीजते असर की द्योतक है। इनमें शिवेंद्र, पुष्पा और किशन सिंह की हार में उनकी बतौर सांसद अकर्मण्यता का खासा हाथ रहा। जहां तक जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह की जीत का सवाल है, उन्हें चुनाव में राजपुरुष होने का कम, जुझारू वृत्ति, खरसिया में अर्जित प्रभामंडल और मतदाताओं से आत्मीय बर्ताव तथा मुकाबले में कमजोर प्रत्याशी होने का ज्यादा लाभ मिला।

टिकट वितरण में अतार्किक दृष्टिकोण कांग्रेस की हार का अहम सबब बना। नये चेहरों और महिलाओं की उपेक्षा ने कांग्रेस के जनाधार को संकुचित किया। कांग्रेस ने तीस प्रतिशत के वायदे को भुलाकर महज तीन महिलाओं प्रवीण कुमारी, पुष्पा देवी और विद्यावती को टिकट दिया और ये तीनों ही पराजित हुईं। जातीय राजनीति और उससे बढ़कर निष्क्रियता से विक्षुब्ध मिथुन मूर्तियों के लिए विख्यात खजुराहो के मतदाताओं ने विद्यावती के खिलाफ गैरिक वसना युवा नेता उमा भारती को प्रदेश में सर्वाधिक एक लाख ९३ हजार मतों से विजयी बनाया। जबकि राजमाता और महाजन को मिलाकर भाजपा की तीनों महिलाएं विजयी रहीं।

अल्पसंख्यक: भाजपा के माथे पर एक और कलगी यह लगी कि होशंगाबाद से उसके सिख प्रत्याशी सरदार सरताज सिंह ने अभा सेवादल के उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा को चुनावी दंगल में पटकनी दे दी। प्रदेश के इतिहास में यह दूसरा और विपक्ष की ओर से पहला अवसर है कि कोई सिख चुनकर लोकसभा में पहुंचा। भाजपा को ऐसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के आरिफ बेग को लोकसभा में पहुंचाने का श्रेय मिला है। आरिफ ने कांग्रेस के असलम शेर खां को हराया। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी अजीज कुरैशी सतना में भाजपा के दादा सुखेंद्र सिंह से हारे।

अल्पसंख्यकों के साथ-साथ इस दफा हरिजनों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों में से उसे अकेले सारंगढ़ में सफलता मिली। जबकि भाजपा के अनुसूचित जातियों के पांच प्रत्याशी रेशमलाल जांगड़े (बिलासपुर), छविराम अर्गल (मुरैना), सत्यनारायण जटिया (उज्जैन), शंकर पहलवान (सागर) और फूलचंद वर्मा (शाजापुर) जीतकर लोकसभा में पहुंचे।

मतदाताओं द्वारा खारिज: प्रकाश चंद्र सेठी

प्रकाशचंद सेठी, विद्यावती चतुर्वेदी, गार्गीशंकर मिश्र, डालचंद जैन और कालीचरण शकरगाय आदि 'साठा सो पाठा' की श्रेणी में आते हैं। मजे की बात है कि मतदाताओं ने इन सभी साठों-पाठों को सबक सिखाया।

खजुराहो की गैरिक जीत: उमा भारती

मध्यप्रदेश	
कुल सीटें लोकसभा	४०
चुनाव हुए	३९
कांग्रेस-इ	८
भाजपा	२६
जनता दल	३
निर्दलीय	२

ऐसे में कांग्रेस को इस बात का संतोष हो सकता है कि आदिवासी बिरादरी ने उसमें आस्था व्यक्त की। कांग्रेस के पांच आदिवासी उम्मीदवार—झाबुआ से दिलीप सिंह भूरिया, धार से सूरज सोलंकी, कांकेर से अरविंद नेताम, बस्तर से मनकूराम सोढी और मंडला से मोहनलाल तथा भाजपा के दो प्रत्याशी—सरगुजा से लरंग साय और सीधी से जगन्नाथ सिंह चुने गये। पूर्व कांग्रेसी मंत्री डा० भंवरसिंह पोर्ते के रूप में भाजपा को यकीनन एक ऐसा आदिवासी नेता मिल गया है, जो आदिवासी अंचलों में भाजपा के लिए नयी जमीन तोड़ सकता है। बहुत संभव है कि भाजपा शहडोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह के खिलाफ डा० पोर्ते को मैदान में उतारे। शहडोल में डा० पोर्ते के बड़े भाई स्वरूप सिंह पोर्ते के देहांत के कारण चुनाव स्थगित हुआ था।

सबक: प्रकाशचंद सेठी, विद्यावती चतुर्वेदी, गार्गीशंकर मिश्र, डालचंद जैन और कालीचरण शकरगाय आदि 'साठा सो पाठा' की श्रेणी में आते हैं। मजे की बात है कि मतदाताओं ने इन सभी साठों-पाठों को सबक सिखाया। कपास, केलों और गन्नों के लिए प्रसिद्ध खंडवा में शकरगाय एक कमजोर प्रत्याशी थे। एक तरह से वहां तनवंत सिंह कीर और ठाकुर शिवकुमार सिंह के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। लड़ाई में शिवकुमार जीते तो नहीं, किंतु उन्होंने एक लाख ३३ हजार ११७ वोट खींचकर शकरगाय को पराजय की गर्त में धकेल दिया। खुद डूबने और पुराने यार को डुबाने के खेल में भाजपा के अमृत तारवाला ने बाजी मार ली। फिलहाल ठाकुर बंधुओं को इसका संतोष हो सकता है कि उन्होंने कीर-बंधुओं की बाजी पलट दी।

यह तय है कि टिकटों में फेरबदल होता तो मप्र में लड़ाई अधिक रोचक व कांटे की होती। जैसी कि एक प्रभावशाली नेता ने कोशिश भी की। अगर रायपुर से श्यामाचरण शुक्ल, खंडवा से ठाकुर महेंद्र सिंह, जबलपुर से परमानंद भाई पटेल और इंदौर से सुरेश सेठ को कांग्रेस टिकट थमाती और सतना अथवा भोपाल से अर्जुन सिंह को उम्मीदवार घोषित करती, तो तय था कि कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल बनता और उसे दहाई सीटें मिलतीं।

—सुधीर सक्सेना, एसपी त्रिपाठी के साथ

४०
३६
८
२६
३
२

संतोष हो
में आस्था
ादिवासी
भूरिया,
द नेताम,
डला से
-सरगुजा
सिंह चुने
तें के रूप
सी नेता
ाजपा के
ाव है कि
ीर सिंह
शहडोल
के देहांत

द्यावती
न और
ठा' की
ताओं ने
कपास,
डवा में
तरह से
ार सिंह
ड़ाई में
क लाख
ाय को
ने और'
अमृत
ठाकुर
उन्होंने

ता तो
होती।
ी की।
वा से
ई पटेल
माती
ह को
कांग्रेस
दहाई

साथ

ज़ो सुरक्षा रेमण्ड सीमेंट से मिले वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले.

इसलिए चाहे आपका अपना घर हो या दफ़्तर या फिर कोई अन्य निर्माण कार्य, भरोसा कीजिए केवल रेमण्ड सीमेंट पर. क्योंकि रेमण्ड सीमेंट ठोस हैं

- इसके फ़ायदे : उत्तम दबाव शक्ति (कम्प्रैसिव स्ट्रैंथ), जमाव का बढ़िया मानक, मज़बूत पैकिंग.

जी हां, रेमण्ड सीमेंट को बरसात, धूप और समय जैसी कुदरत की फौलादी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है.

याद रखिए, रेमण्ड सीमेंट के कण-कण में भरी है सर्वोत्तम सुरक्षा और सर्वोत्तम शक्ति.

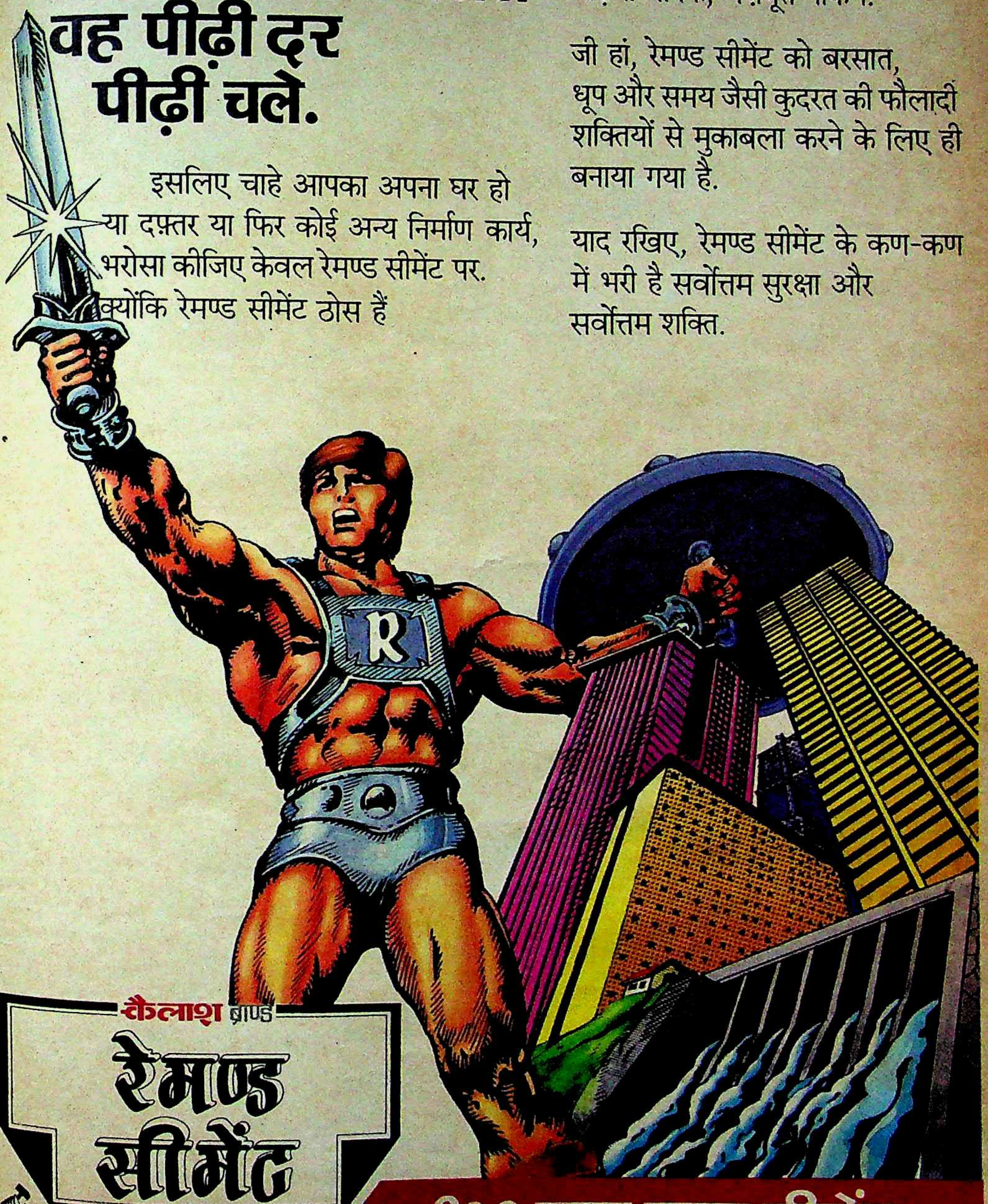

कैलाश ब्रांड

रेमण्ड सीमेंट

१०० साल वाला सीमेंट

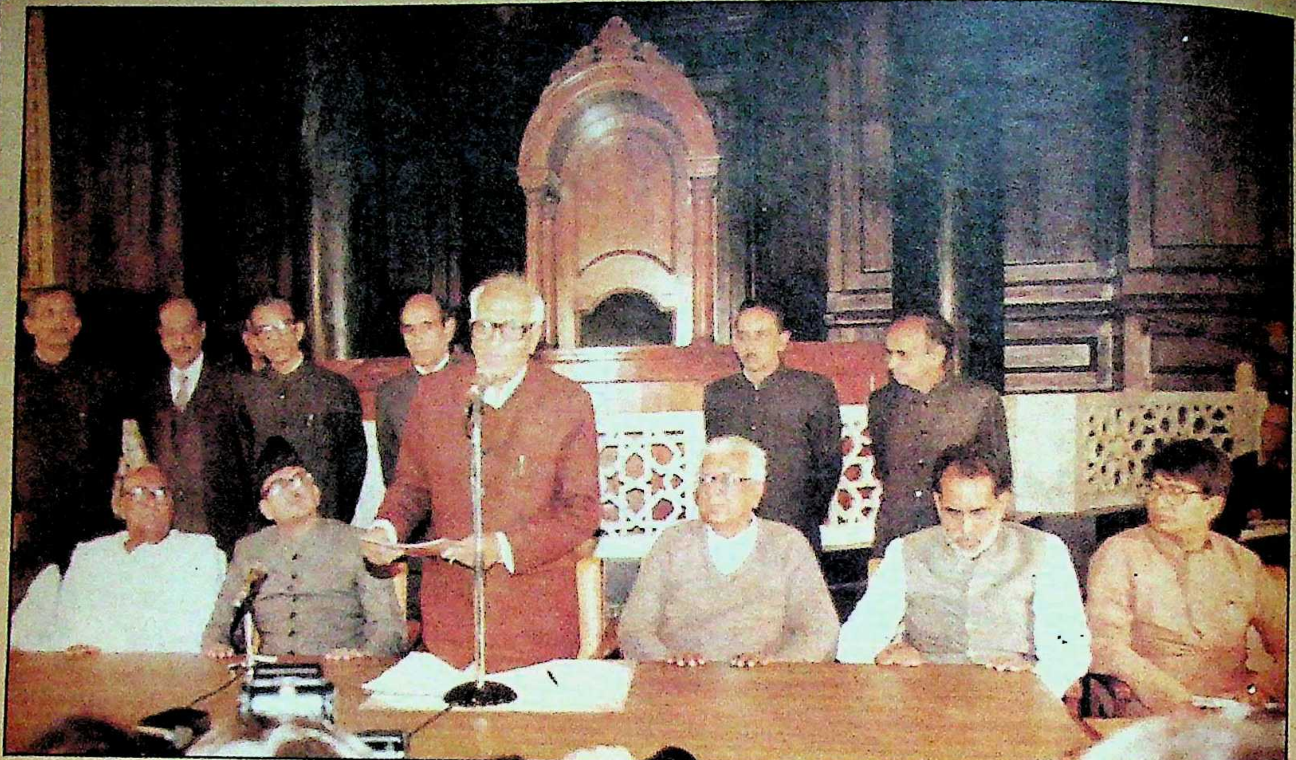

ताऊ का खेल : मधु दंडवते जनता दल के संसदीय दल के नेता के रूप में वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव करते हुए। बायें से रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक, वीपी सिंह, मधु दंडवते, देवीलाल, चंद्रशेखर और अजीत सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

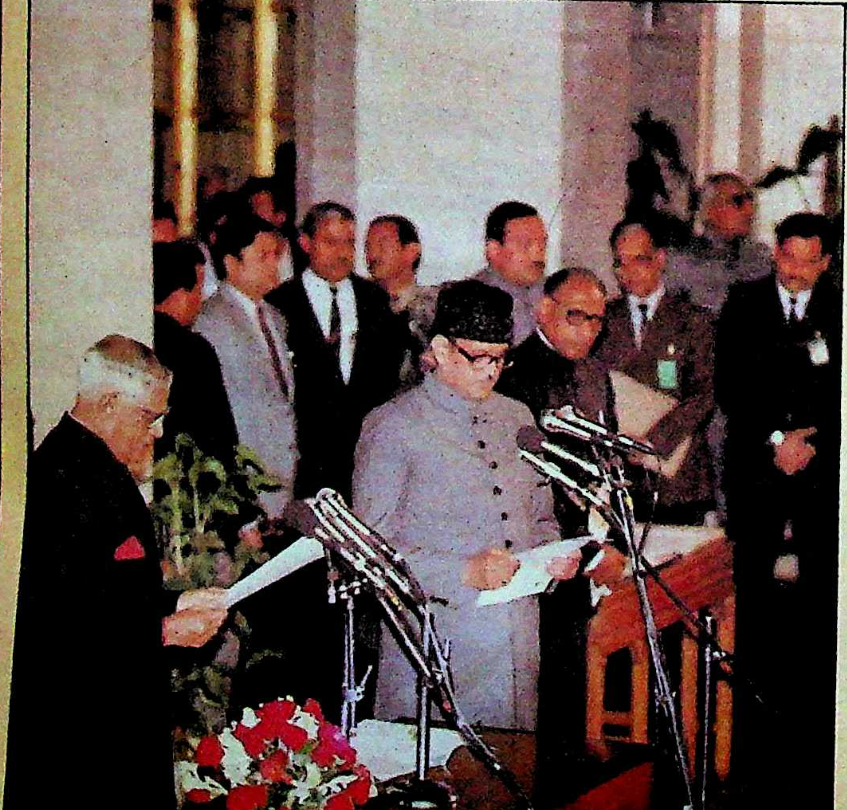

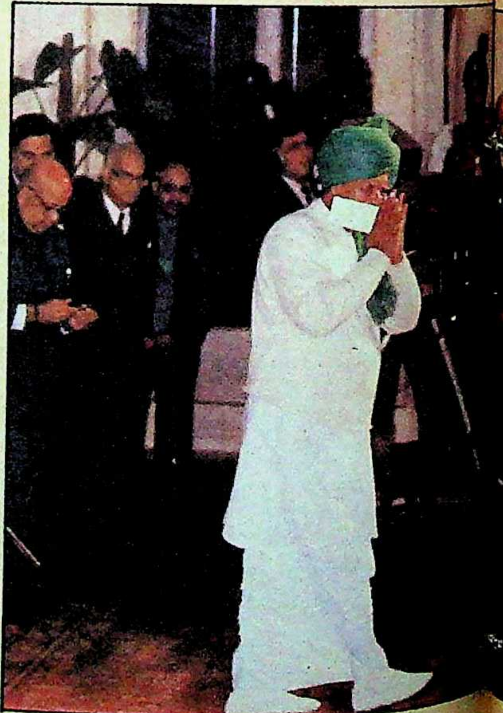

जो कहा, कर दिखाया : शपथ ग्रहण करने के बाद अतिथियों का अभिवादन करते हुए देवीलाल

जनशक्ति की विजय : प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए वीपी

छाया : सुनील सक्सेना

दो-दो हाथ के बाद : वीपी सिंह को बधाई देते हुए राजीव गांधी

छाया : सुनील सक्सेना

किसान की ताकत : उप प्रधानमंत्री देवीलाल को बधाई देते हुए राजीव गांधी, साथ में वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और वीपी सिंह

छाया : सुनील सक्सेना

विरासत में राजनीति :
प्रधानमंत्री के शपथ-समारोह से सपरिवार लौटते हुए अजीत सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

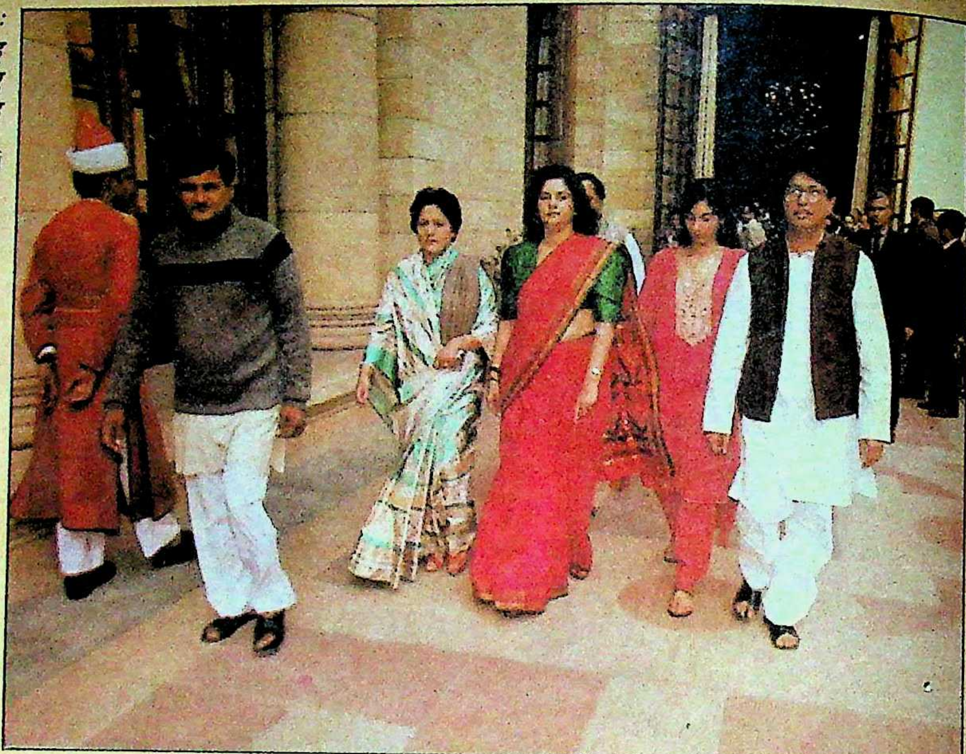

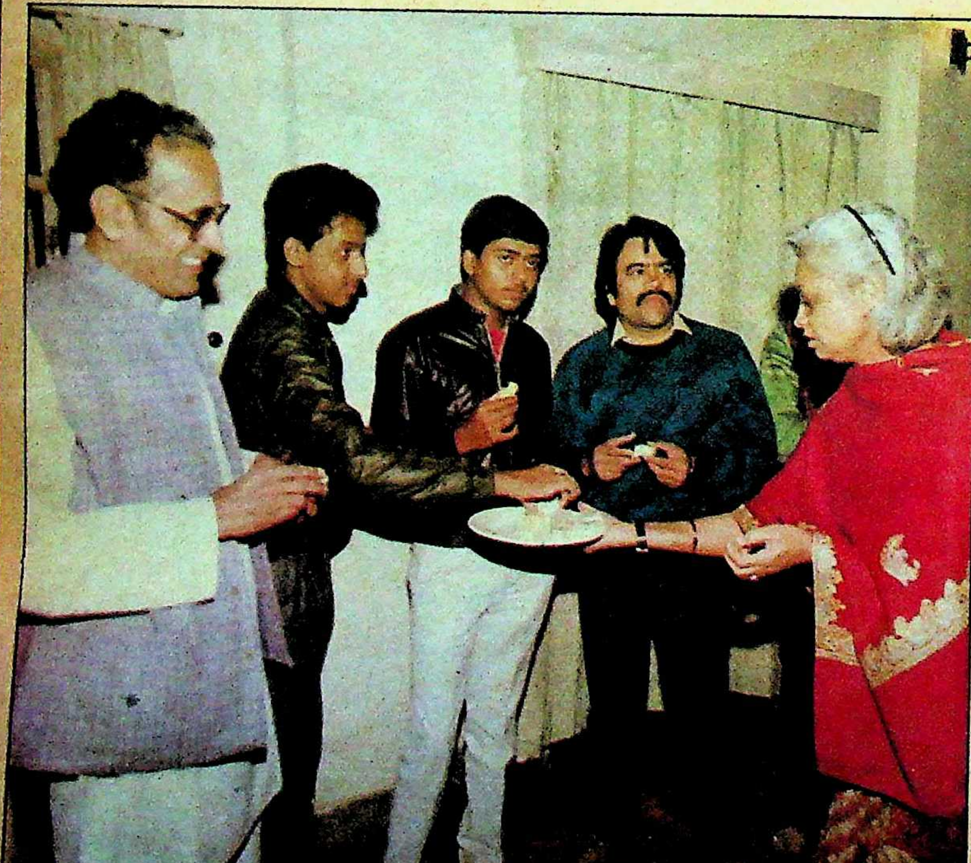

सत्ता की मिठाई :
श्रीमती सीता देवी बधाई स्वीकार करते हुए

छाया : मनमोहन शर्मा

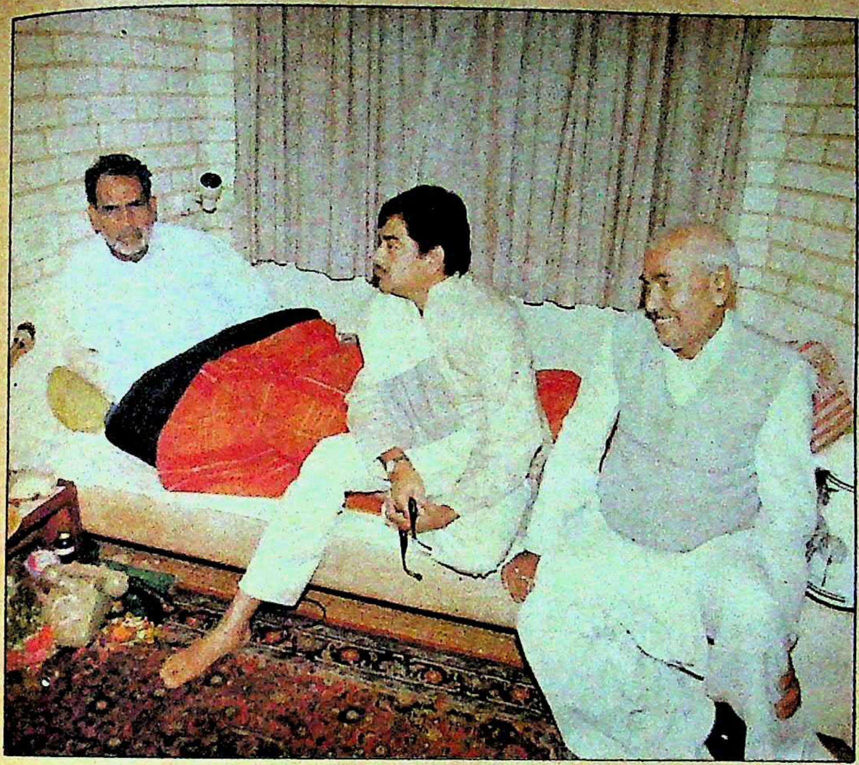

तनाव के क्षण :
चंद्रशेखर का हालचाल
लेते हुए शत्रुघ्न सिन्हा और
ओमप्रकाश चौटाला

छाया : मनमोहन शर्मा

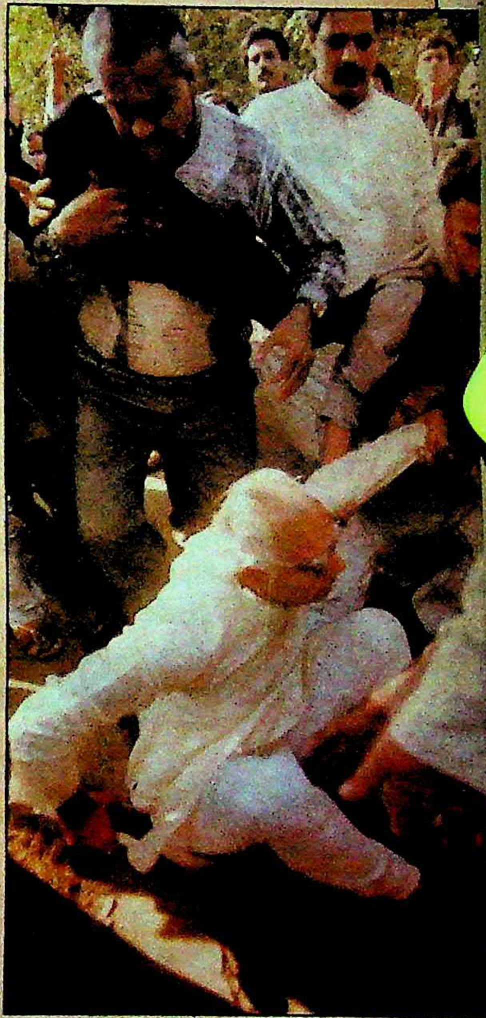

जो कांग्रेसियों तक ने
नहीं किया : चंद्रशेखर के घर के पास
रामजेठमलानी की पिटाई

छाया : सुनील सक्सेना

टकराव की मुद्रा में : उप्र के मुख्यमंत्री की दौड़ में अजीत सिंह (बायें) और मुलायम सिंह यादव

छाया : मनमोहन शर्मा

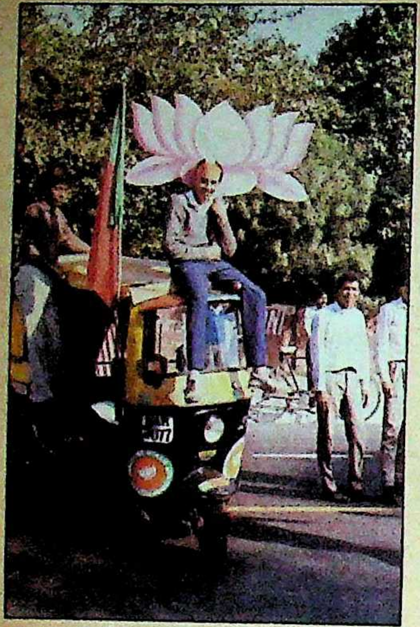

भाजपा चुनाव चिह्न का
कट आउट लिये थ्री ह्वीलर की छत पर
बैठा एक कार्यकर्ता

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

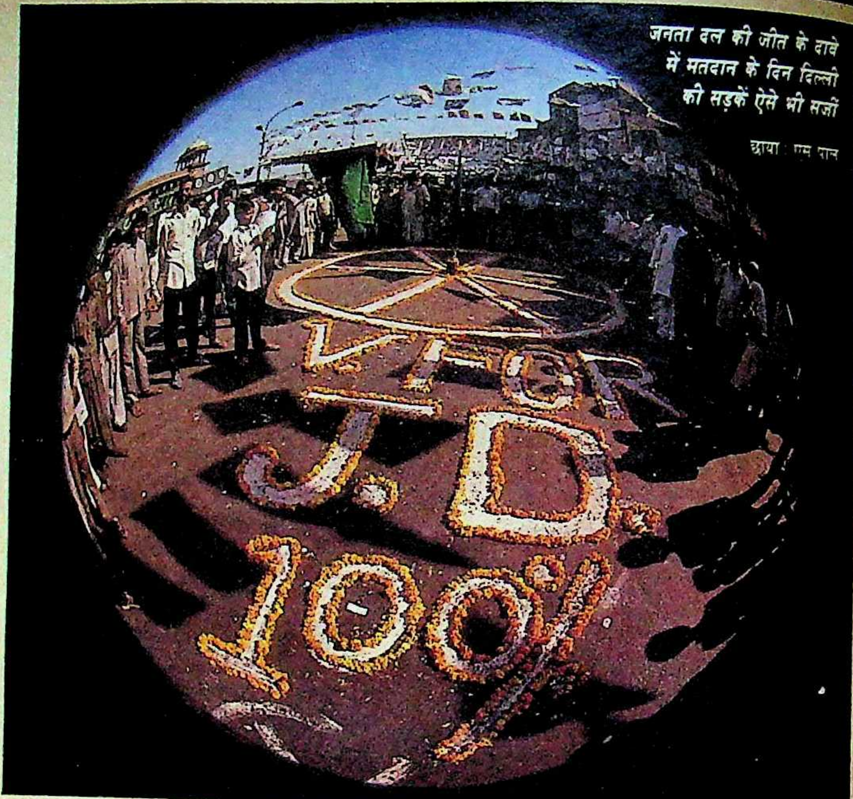

जनता दल की जीत के दावे
में मतदान के दिन दिल्ली
की सड़कें ऐसे भी सजीं

छाया : एम पाल

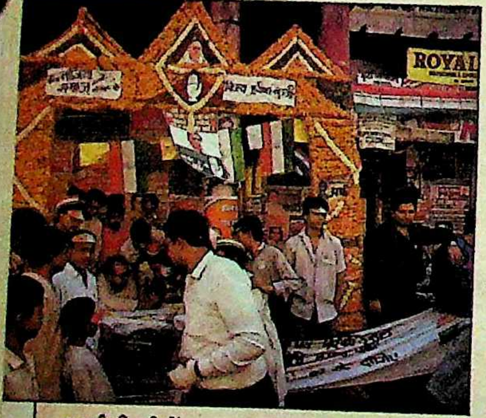

पुरानी दिल्ली में
गेंदे के फूलों से बना एक गेट
जहां पर मतदान के लिए पर्चियां
बन रही थीं

छाया : एम पाल

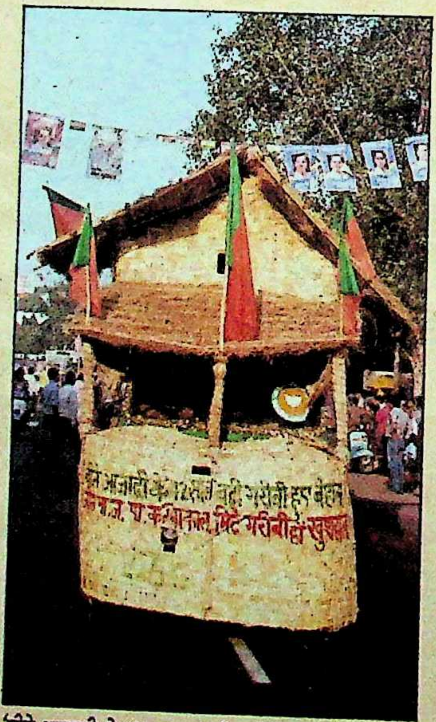

'बीते आजादी के ४२ साल, बढ़ी गरीबी,
हुए बेहाल, जीते भाजपा-मिटे गरीबी, हो खुशहाल' नारे से
सुसज्जित प्रचार वाहन

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

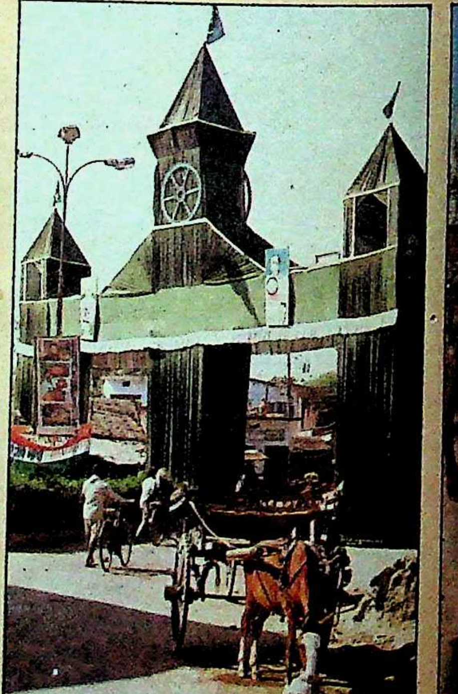

अमेठी बाजार में
जनता दल का भव्य द्वार

छाया : राजेंद्र कुमार

के दावे
दिल्ली
ी सजी
ग्स पार

अमेठी के एक पोलिंग बूथ पर
बूथ कैप्चरिंग के बाद पहुंचे सीआरपी के
जवान और अधिकारी

छाया : मनमोहन शर्मा

अमेठी के एक मतदान केंद्र पर
संजय सिंह एक वृद्ध मतदाता से बात करते
हुए, साथ में उनके समर्थक।

छाया : मनमोहन शर्मा

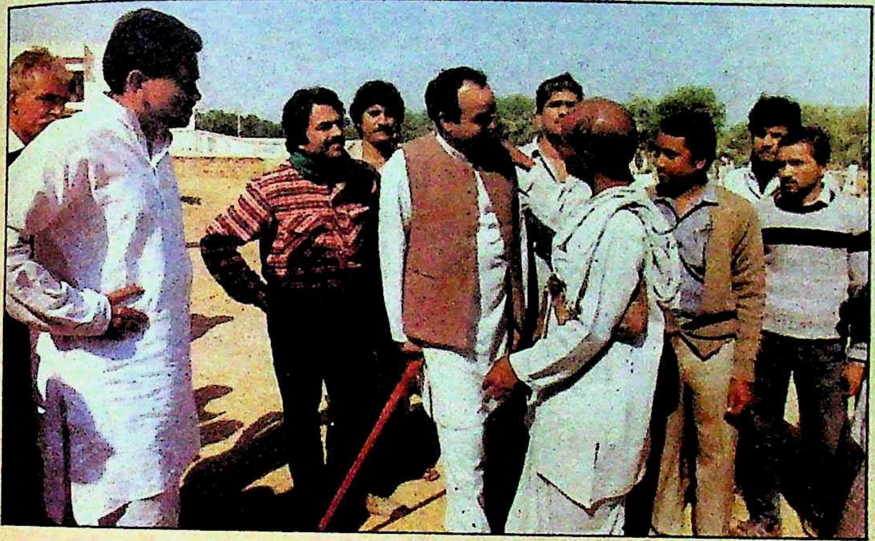

फ़तेहपुर के डुमरई गांव में
वीपी सिंह पर गोली चलने के बाद पुलिस
की मोर्चाबंदी

छाया : मनमोहन शर्मा

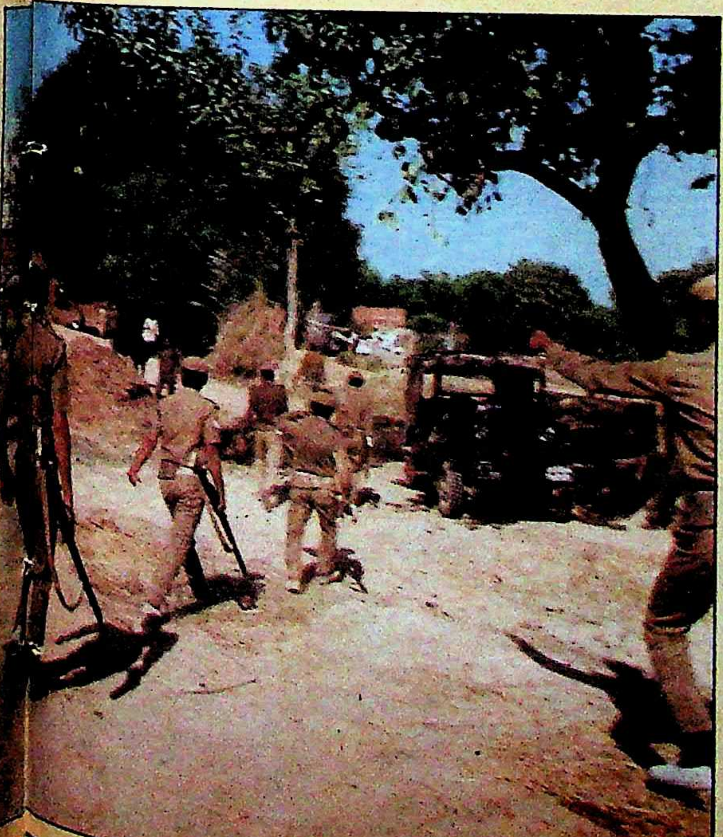

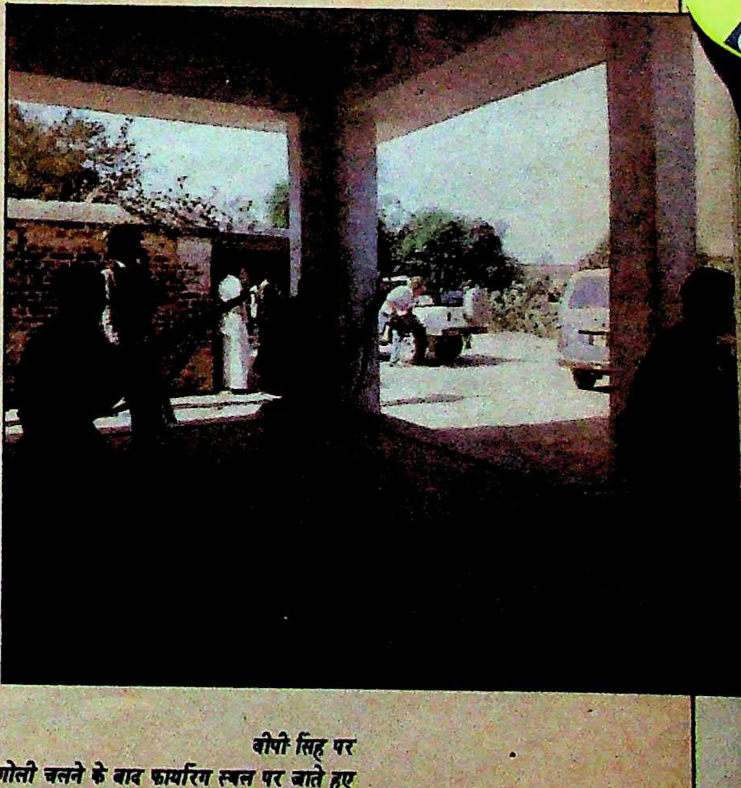

वीपी सिंह पर
गोली चलने के बाद फायरिंग स्थल पर जाते हुए
पुलिस के शस्त्रधारी जवान

छाया : मनमोहन शर्मा

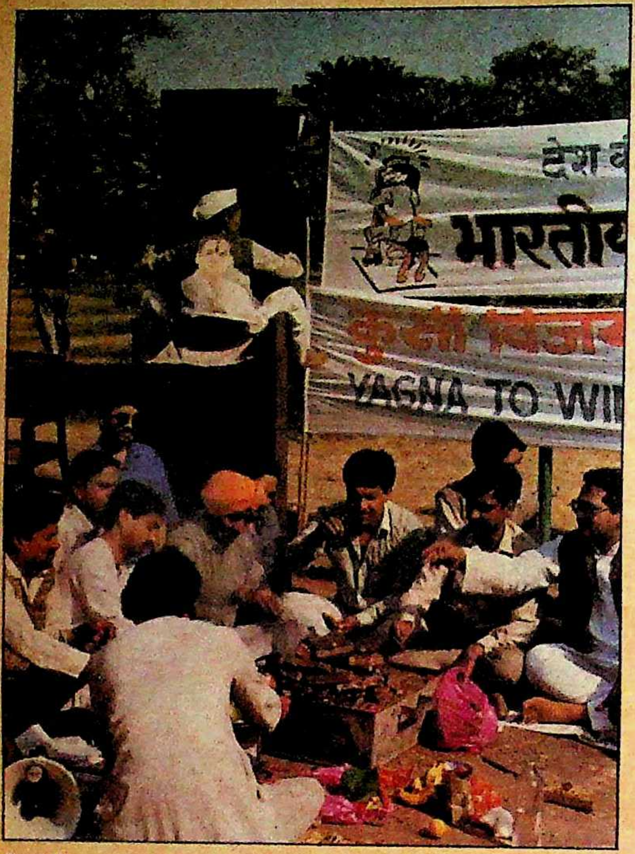
देश के
भारतीय
कुर्सी विजय
YAGNA TO WIN

दिल्ली के कनाट सर्कस पर विरोधी दल के कार्यकर्ता

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

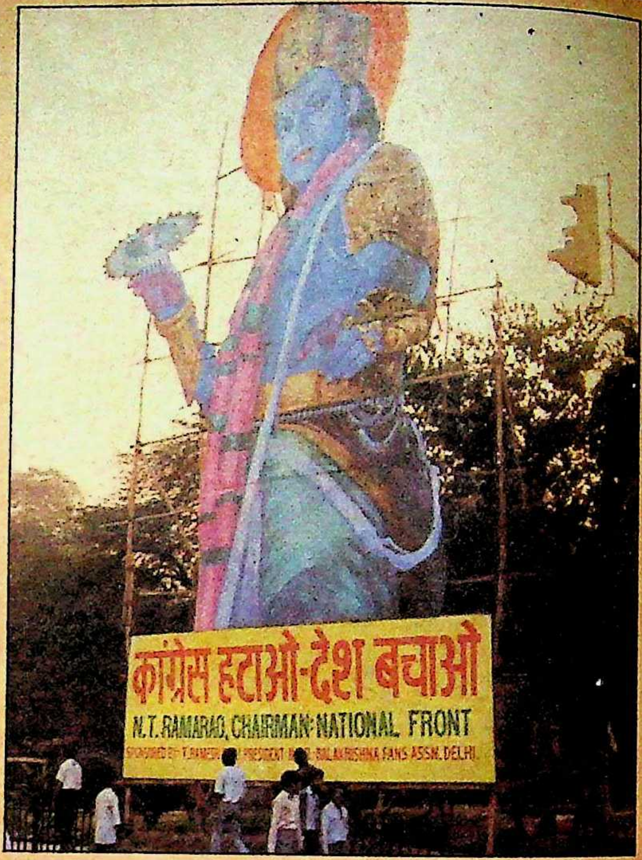
कांग्रेस हटाओ-देश बचाओ
N.T. RAMARAO, CHAIRMAN-NATIONAL FRONT

दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर एनटीआर का विवादास्पद कट आउट जिसे बाद में चुनाव आयोग के आदेश पर हटा दिया गया

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

अनिल शास्त्री (इनसेट) का विजय जुलूस

छाया : क्लाउन

उड़ीसा

जनरोष की ज्वलंत जीत

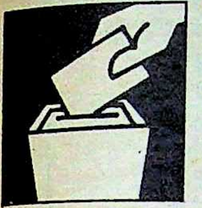

उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जानकीवल्लभ पटनायक और प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष कांहूचरण लेंका उन महान इकाइयों में हैं जिन्हें बेआबरू होने के बाद ही यथार्थ का बोध होता है। राज्य में २२ नवंबर को हुए संसदीय चुनावों के यथार्थ को भी उन्होंने तभी स्वीकारा जब २६ नवंबर की रात में चुनाव-परिणामों के रुख से साफ हो गया कि राज्य की २१ लोकसभा सीटों में से १८ जद के नेतृत्ववाले तीन दलों के गठबंधन की झोली में जा रही हैं। हुआ भी यही। सारे नतीजे आ जाने के बाद पटनायक और लेंका ने चुनाव में पार्टी की पराजय की जिम्मेवारी ली, तब एक बुजुर्ग कांग्रेसी की टिप्पणी थी, "अब जिम्मेदारी लेने से क्या होता है? जिम्मेदारी का ख्याल उस वक्त किया होता जब आपसी लड़ाई में पार्टी टूट-बिखर रही थी। उस गृहयुद्ध के नायक आप दोनों (पटनायक और लेंका) थे न!"

सत्ता का चौसर: १९७७ के जबर्दस्त जनता लहरवाले आम चुनाव में भी कांग्रेस-इ उड़ीसा में इतनी बेआबरू नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई। तब जपा और उसकी सहयोगी पार्टी माकपा को १७ सीटें ही मिली थीं। १९८० की जपा विरोधी हवा और १९८४ की इंदिरा गांधी की मृत्यु से चली सहानुभूति लहर की बदौलत कांग्रेस-इ ने क्रमश: २० और २१ सीटें हासिल की थीं। १९८० और १९८५ के विधानसभा चुनावों में भी इंका ने ५० फीसदी वोटों के साथ राज्यविधानसभा की १४७ में से ११७ सीटें प्राप्त की थीं। लेकिन इन सफलताओं और सत्ता के मद में उड़ीसा कांग्रेस-इ के कर्ताधर्ता यह भूल गये कि यह जीत लहर की बदौलत मिली है, पार्टी और उसके नेताओं की छवि के कारण नहीं। नतीजतन राज्य के मतदाताओं में पार्टी की जो छवि १९७७ के पूर्व रही, गत चार सालों में उससे भी बिगड़ गयी। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार, निरंकुशता और जनहित की उपेक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के कारण पार्टी बदनाम हो चुकी थी। कोई लहर न होने के कारण कांग्रेस पार्टी और सरकार की करनी-भरनी के आधार पर ही मतदाता को फैसला देना था और राज्य की जनता के हित में अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए पार्टी के पास कुछ नहीं था, सिवा झूठ के। जनता की शिकायतें अनेक थीं। महंगाई, जरूरी सामानों का अभाव, बेरोजगारी, असुरक्षा, सूखा और तूफान जैसी विपदाओं के समय भी पीड़ितों की उपेक्षा, दुर्बलों और अबलाओं पर अत्याचार, पत्रकारों का उत्पीड़न, अराजक तत्वों को बढ़ावा आदि समस्याओं से आम जनता पिटती रही, रोती-चीखती रही। लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता पीड़ित जनता के आंसू पोंछने न जाकर सत्ता और पद का चौसर खेलते रहे।

जेबी पटनायक

एक कोण पर मुख्यमंत्री जेबी पटनायक की फौज थी, तो दूसरे पर प्रदेश इंका प्रमुख लेंका की। तीसरे कोण पर पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी के समर्थक डटे रहे। चुनाव की घोषणा होने पर टिकट-वितरण की खींचतान में पार्टी और बेदम हो गयी।

इंकाविरोधी हवा: जहां एक ओर राज्य की जनता का मन कांग्रेस-इ से भर गया था, वहीं दूसरी ओर इंका का त्रिकोणीय अंतकर्लह अंत तक चलता रहा। "एक कोण पर मुख्यमंत्री जेबी पटनायक की फौज थी, तो दूसरे पर प्रदेश इंका प्रमुख लेंका की। तीसरे कोण पर पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी के समर्थक डटे रहे। चुनाव की घोषणा होने पर टिकट-वितरण की खींचतान में पार्टी और बेदम हो गयी," क्योंकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में दलीय भावना या आपसदारी जैसी कोई चीज रह ही नहीं गयी। क्षेत्रीय मुद्दों के कारण तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की जनता सत्तारूढ़ दल से खफा थी। मसलन बालासोर संसदीय क्षेत्र के लोग बलियापाल में राष्ट्रीय परीक्षण रेंज बनाये जाने से क्षुब्ध होकर सत्तारूढ़ दल को हराने का निर्णय बहुत पहले ले चुके थे।

राज्य में कांग्रेस-विरोधी हवा के बावजूद सत्तारूढ़ दल के नेता न तो दलीय एकता कायम कर सके और न किसी दूसरी पार्टी से तालमेल बिठा पाये। पार्टी सभी २१ सीटों पर लड़ी। इसके विपरीत जनता दल ने एक-एक सीट देकर भाकपा और माकपा से समझौता किया और एक सीट पर निर्दल प्रत्याशी का समर्थन किया। १८ सीटों पर जद ने अपने प्रत्याशी खड़े किये। इस तालमेल और आपसदारी की बदौलत अपने विजय अभियान में जनता दल ने न केवल सत्तारूढ़ दल के बड़े-बड़े महारथियों को धूल चटा दी, बल्कि १३ सीटों पर चुनौती देनेवाली जपा और ६ सीटों के लिए मैदान में आयी भाजपा का भी सफाया कर दिया।

जनरोष का विस्फोट: उड़ीसा में लोकसभा के चुनाव-परिणामों ने राज्य में गहराई तक व्याप्त जनरोष को उजागर किया है। यह आमतौर पर कांग्रेस-इ और खासतौर से जेबी पटनायक के नौ साल के निर्मम-निरंकुश शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा ही था जो इस चुनाव में जनादेश बनकर सामने आया है। पटनायक के 'परिवार के शासन' से लोग किस हद तक नाराज थे, इसका अंदाज जद प्रत्याशियों की शानदार जीत के मुकाबले इंका प्रत्याशियों की दयनीय हार से किया जा सकता

बीजू पटनायक

विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। दूसरी ओर संसदीय चुनावों में तीन दलीय मोर्चे के सूत्रधार की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक राज्य में पुन: सत्तारोहण की पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं।

स्पा
डिटर्जेंट केक
ज़बरदस्त झाग! किफ़ायती धुलाई!

ज़बरदस्त झाग

किफ़ायती धुलाई

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा

डिटर्जेंट केक

A *Kusum* Product

विश्वास के साथ खरीदिये

Contract KP. 96-86 HIN

है। कटक की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर पटनायक की पत्नी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस-इ की अध्यक्ष जानकी पटनायक को जद विधायक श्रीकांत जेना ने २ लाख ४ हजार मतों से हराकर नया कीर्तिमान बनाया। इसके पहले हार-जीत का कीर्तिमान २ लाख ३ हजार ५७३ मतों का अंतर था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी सिंह देव ने १९८४ में ढेंकानल संसदीय सीट जीतकर कायम किया था। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जनरोष का आलम यह था कि १९८४ के हीरो उन्हीं केपी सिंह देव को इस बार जद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भजमान बहेरा से १ लाख २३ हजार मतों से मुंह की खानी पड़ी। जानकी पटनायक और देव दोनों जिन सीटों पर दो बार सांसद रह चुके थे, उन्हें इस बार जायज-नाजायज सारी शक्ति लगाकर भी नहीं बचा पाये। कटक और ढेंकानल के अलावा दस और संसदीय क्षेत्रों—बालासोर, भद्रक, पुरी; भुवनेश्वर, जगतसिंहपुर, असका, संबलपुर, देवगढ़, बोलनगिर और केयोंझार—में भी जद-भाकपा-माकपा मोरचे के उम्मीदवारों ने इंकाई महारथियों को एक-एक लाख से अधिक मतों से पछाड़ा। भाकपा और माकपा सिर्फ एक-एक सीट पर लड़ीं और बुलंदी से जीतीं। भाकपा प्रत्याशी लोकनाथ चौधरी ने जगतसिंहपुर की और माकपा प्रत्याशी शिवाजी पटनायक ने भुवनेश्वर की सीट कांग्रेस-इ से छीन ली, तो जद-समर्थित निर्दल प्रत्याशी बालगोपाल मिश्र ने सांसद एवं पूर्व प्रदेश इंकाध्यक्ष नित्यानंद मिश्र को १.६८ लाख मतों से हराकर बोलनगिर की सीट पर कब्जा कर लिया।

राज्य के इस संसदीय समर में विपक्षी मोरचे की शानदार जीतों में एक रही पुरी लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीलमणि राउतराव (जद) की विजय। वहां पूर्व केंद्रीय उपमंत्री और राज्य के पूर्व विधानसभा-अध्यक्ष तथा मंत्री ब्रजमोहन महंती १.३९ लाख मतों से पिट गये। मोरचे की दूसरी उल्लेखनीय विजय केंद्रपाड़ा में दर्ज हुई जहां पूर्वमंत्री और जद प्रत्याशी रवि राय ने इंका के भगवतप्रसाद महंती को करीब ६२००० मतों से हराया।

जनता दल को मिली बाकी छह सीटों पर भी जीत-हार के बीच कम-से-कम ५० हजार वोटों का फर्क रहा। देवानंद अमत ने जहां ९२ हजार मतों की बढ़त के साथ सुंदरगढ़ की सीट हासिल की, वहीं आनंदी दास ने जयपुर की सीट पर ७९००० मतों से इंका प्रत्याशी को हराया। कालाहांडी की प्रतिष्ठाजनक सीट (जिस पर, कालाहांडी राज परिवार के उदित प्रताप देव के मैदान में आ जाने से, तिकोनी लड़ाई थी) हरिजन विधायक भक्तचरण दास ने अपने इंका प्रतिद्वंद्वी जगन्नाथ पटनायक को ५२ हजार मतों से हराकर विजय प्राप्त की। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और जद प्रत्याशी समरेंद्र कुंडू ने बालासोर की सीट पर इंका सांसद चिंतामणि जेना को भारी मतों से हराया। इसी तरह नकुल नाइक (जद) ने फूलबनी सीट इंका प्रत्याशी को ५९ हजार मतों से हराकर हासिल की। सबसे कम अंतर की जीत एकमात्र मयूरभंज की सीट पर रही जहां झारखंडियों के आतंक से मात्र ३८ प्रतिशत मत पड़े। वहां जद प्रत्याशी, आईएएस अधिकारी से नेता बने भागेय गोवर्धन ने उपमंत्री श्रीमती हेंब्रम सरस्वती को १७००० मतों से पराजित किया।

विधानसभा पर संकट: उड़ीसा में लोकसभा चुनाव का यह पहला मौका है जब मतदाताओं ने पूर्व रजवाड़ों के वंशजों को तरजीह नहीं दी। नतीजतन, जहां कालाहांडी में पूर्व शासक राजा प्रतापकेशरी देव के ज्येष्ठ पुत्र उदित प्रसाद देव (भाजपा) हार गये, वहीं बालासोर में पौना के पूर्वराजा स्व० आरएन सिंह देव के ज्येष्ठ पुत्र राज सिंह देव (भाजपा) की जमानत जब्त हो गयी। ढेंकानल में इंका टिकट पर लड़े वहां के राजा कामाख्याप्रसाद सिंह महेंद्र बहादुर (जो केंद्र में राज्यमंत्री भी रह चुके हैं) को भी करारी मात खानी पड़ी। जैसे-तैसे पारलखमुंदी के महाराजा गोपीनाथ गजपति नारायण देव (इंका) जद के सूर्यनारायण पात्र को १४००० मतों से हरा सके।

इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल लोकसभा की अपनी २१ सीटों में से मात्र तीन को बचा सका, वह भी पहले की अपेक्षा काफी कम वोटों की बढ़त से। केंद्रीय संचार राज्यमंत्री गिरिधर गोमांगो कोरापुत की सीट पर लगातार पांचवीं बार जीते। १९८४ में जहां वे करीब एक लाख वोटों से आगे रहे, वहां इस बार मात्र ४५००० मतों की बढ़त पा सके। नौरंगपुर सीट पर खगपति प्रधान जहां '८४ में १.०४ लाख से जीते थे, वहां इस बार ३४००० मतों से ही जीते। इस दयनीय स्थिति के साथ ही, कांग्रेस-इ के लिए अपनी राज्य सरकार को बरकरार रखना कठिन हो गया है। अगले तीन महीनों में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव में विजयी होने के बाद जनता दल के नेता जोर-शोर से विधानसभा भंग करने और चुनाव कराने की मांग करने लगे हैं। अगर ये चुनाव हाल ही हुए, तो तय है कि उड़ीसा में कांग्रेस-इ का पत्ता साफ हो जायेगा। वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल १३ मार्च, १९९० तक ही है। इसके पूर्व ही "राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। दूसरी ओर संसदीय चुनावों में तीन दलीय मोर्चे के सूत्रधार की भूमिका में सफल जद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक राज्य में पुन: सत्तारोहण की पृष्ठिभूमि तैयार कर चुके हैं।"

—वशिष्ठ

नेता के दरस को मतदाता तरसे

उड़ीसा में लोकसभा के दो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों, भद्रक और जयपुर के अनुसूचित जाति समुदाय के लगभग २० लाख मतदाता अपने भावी प्रतिनिधियों को देखने के लिए तरस गये। बालेश्वर जिले में एक-दूसरे से जुड़े इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दस दिन पहले तक कोई प्रत्याशी आया ही नहीं। बाद में जद और कांग्रेस-इ के प्रत्याशी आये भी, तो इतने कम समय तक इन क्षेत्रों में रहे कि मतदाताओं को पता ही नहीं चला।

जयपुर क्षेत्र की एक और खासियत यह रही कि इस सीट के दोनों दावेदार इस बार पाला बदल चुके थे। सचमुच भजनलाल का-सा प्रकरण था। जिस आनंदीचरण दास ने १९८४ में कांग्रेस-इ के टिकट पर जयपुर की सीट जीती थी, वे इस बार जनता दल के प्रत्याशी थे। जो रामचंद्र मल्लिक जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में '८४ का चुनाव हार गये थे, वे इस बार कांग्रेस-इ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों नेताओं के पाला बदलने से जयपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव बड़ा मजेदार हो गया था। मतदाता दोनों प्रत्याशियों के बारे में एक-से-एक फिकरे कसते रहे। लेकिन प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं और प्रचारकों ने क्षेत्र में आने में बहुत देर कर दी, जबकि पहली बार इस सीट के लिए सात उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। दास और मल्लिक के अतिरिक्त तीन निर्दल प्रत्याशी थे। एक-एक उम्मीदवार दूरदर्शी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के थे। '८४ में इस सीट के चार ही दावेदार रहे।

बहरहाल क्षेत्र में प्रचार के लिए प्रतिद्वंद्वी दलों के आने के पूर्व ही मतदाता—जो व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दे रहे थे—अपने प्रतिनिधि के बारे में निर्णय ले चुके थे। फलत: इस चुनाव में जद के प्रत्याशी आनंदीचरण दास ने इंका के मल्लिक को करीब ६९००० मतों से हरा दिया।

भद्रक (सु) संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को भी प्रत्याशियों की झलक मिलने के पहले ही अपने प्रतिनिधि के बारे में निर्णय लेना पड़ा। इस सीट के पांच दावेदार थे, पर लड़ाई कांग्रेस-इ के सांसद अनंतप्रसाद सेठी और जद प्रत्याशी मंगाराज मल्लिक के ही बीच थी। शेष तीन में दो निर्दल थे और एक जपा उम्मीदवार। '८० के चुनाव में यह सीट मल्लिक को मिली थी। '८४ में सेठी ने यह सीट मल्लिक से छीन ली। इस बार मंगाराज मल्लिक ने सेठी को एक लाख से अधिक मतों से हराकर इस पर फिर कब्जा जमा लिया है।

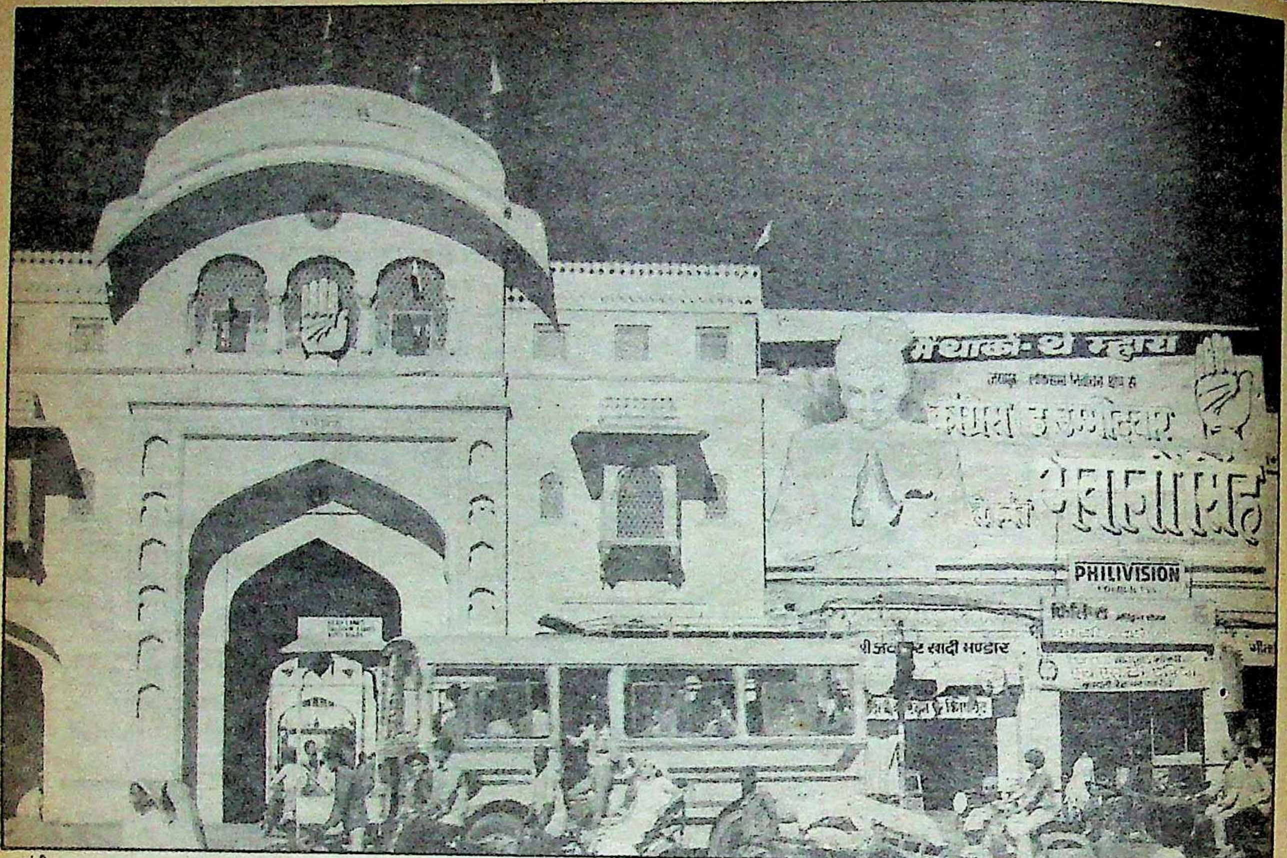

सामंती पराजय

राजस्थान

कांग्रेस-इ की पराजय का किस्सा

जिन हरिदेव जोशी से कांग्रेस आलाकमान को परहेज था, उन्हीं जोशी को चुनाव में फजीहत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का आसन ससम्मान सौंप दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस के पराभव में किन मुद्दों ने भूमिका निभायी?

नवीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने राजस्थान से कांग्रेस-इ की लोकसभा में हिस्सेदारी पूरी तरह से समाप्त कर दी है। सन १९८४ में राजस्थान के मतदाता ने यही हालत विपक्ष की की थी। उस वक्त राजस्थान का मतदाता कांग्रेस-इ के पक्ष में इतना मुखर था कि विपक्ष के सफाये का दावा बेमानी नहीं लगता था। पर इस बार मतदान से पूर्व तक मतदाता की खामोशी कांटे के संघर्ष का अहसास भर कराती थी। विपक्ष के भारी होने का हलका-सा अहसास केवल उसके नियोजित चुनाव प्रचार और सीधे मुकाबले से होता था। विपक्ष द्वारा इस बार एक नोट और एक वोट की बात केवल कहने भर के लिए थी। बावजूद इसके उसके प्रचार साधन सत्ताधारी दल के मुकाबले हलके नही थे। मसलन कांग्रेस के झंडे अगर सस्ते खादी के बने थे, तो भाजपा के कृत्रिम रेशम के झंडे लगे थे। कांग्रेस-इ झंडों का आकार आधा फुट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकी जबकि भाजपा के प्रदेश के कस्बों और शहरों में लहराते झंडे आधा मीटर से छोटे नहीं थे। दूरदर्शन अगर कांग्रेस-इ का भांड़ बना था, तो कुछ प्रांतीय अखबार भाजपा के मुखपत्र बने थे।

इसी तरह प्रदेश के नतीजों की तुलना सन १९७७ की जनता लहर के परिणामों से भी नहीं की जा सकती। जनता लहर के दौरान मतदाता तन-मन-धन से विपक्ष के साथ था, पर इस बार उसका सहयोग केवल मतों तक सीमित रहा है। उस लहर में जाति-धर्म और हिंसा का रोल नहीं था, पर इस बार इनका असर कारगर रहा है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता इसे नकारते रहे हैं जबकि पक्ष-विपक्ष के प्रत्याशियों ने स्थानीय जरूरतों के मुताबिक इन्हें पनाह दी। मसलन जयपुर में भाजपा का प्रत्याशी पूरी तरह से हिन्दू मतों को आकर्षित करने में जुटा रहा तो कांग्रेस-इ ने अल्पसंख्यकों को अपना आधार बनाकर चुनाव लड़ा। अल्पसंख्यकों के कांग्रेसी वोट बैंक के जवाब में भाजपा ने प्रदेश के हिन्दू मतों को अपनी गिरफ्त में रखने के सारे हथकंडे अपनाये। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और शिव सेना जैसे संगठन भाजपा के प्रत्याशियों के लिए विशेष प्रचार करते देखे गये।

कथित एक परिवार की सत्ता समाप्त करने के लिए विपक्ष के प्रत्याशियों को मतदाताओं के सामने ऐसी-ऐसी बातों का खुलासा करना पड़ा जिनका समर्थन वे सामान्य स्थितियों में करने से कतरा जाते। मसलन झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित जद प्रत्याशी एडवोकेट जगदीप धनकड़ को अपने निर्वाचन क्षेत्र के राजपूत मतदाताओं के

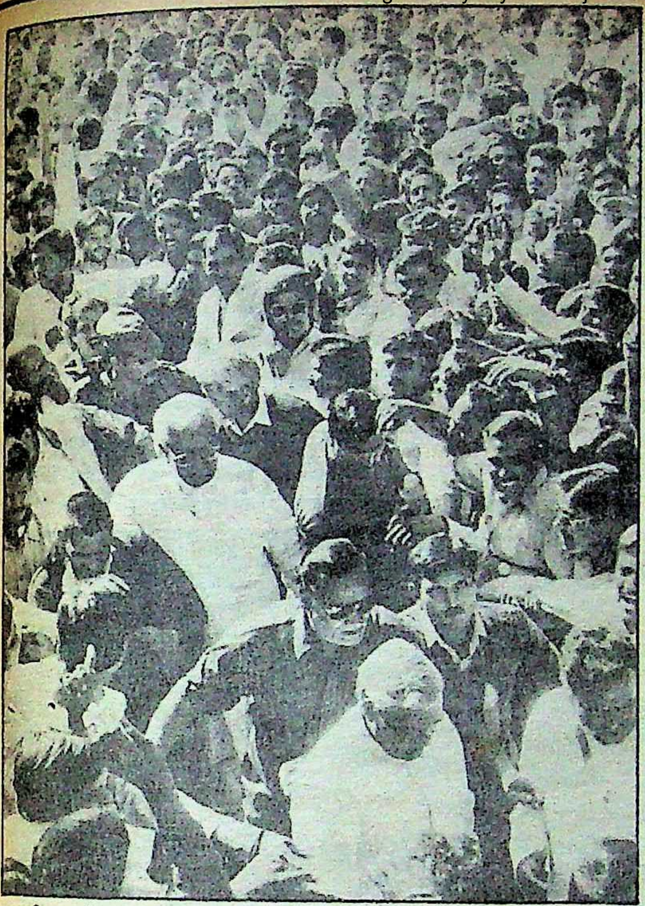

जनशक्ति का सैलाब : देवीलाल और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा साथ-साथ चुनाव प्रचार

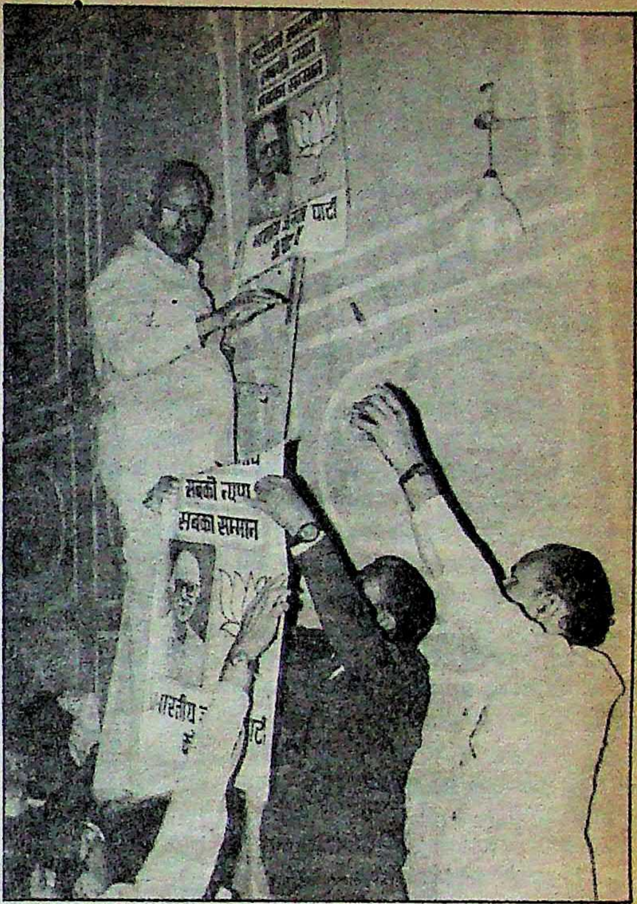

संगठन के प्रति निष्ठा : भाजपा के पूर्व सांसद सतीश चंद्र अग्रवाल चुनाव पोस्टर लगाते हुए

मत हासिल करने के लिए कहना पड़ा कि वे दिवराला 'रूप कंवर दाह-कांड' के मुजरिमों को बचानेवाले वकील रहे हैं। कांग्रेस-इ के प्रत्याशी अयूब खां को वोटों के लिए झुंझुनूं शहर के सती मंदिर में पुनः पूजा-अर्चना की वकालत करनी पड़ी। असम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भाजपा के प्रत्याशी गुमानमल लोढ़ा ने पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिन्दू मतों को हासिल करने के लिए रामशिला पूजन के प्रदेश आयोजन का संचालन भार संभाला। यहां पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान विपक्ष का महत्वपूर्ण घटक जनता दल अपने सहयोगी दल भाजपा और आरएसएस को इनके लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। यही विपक्ष जब एक होकर चुनाव मैदान में खड़ा हुआ, तो आरोप-प्रत्यारोप गौण कर 'राजीव हटाओ' के प्रलाप तक सीमित हो गया।

लगभग ऐसी ही मनःस्थिति के साथ कांग्रेस-इ प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। 'हिन्दू राष्ट्र' की परिकल्पना को रद्द किये बगैर वे अपने पारंपरिक मतदाताओं के बीच पहुंचे, पर अल्पसंख्यकों के मतों को समेटने की उनकी इच्छा ने उन्हें आम मतदाता के मन में लोकप्रिय नहीं होने दिया। अल्पसंख्यकों के अतिवादी रुख को रद्द करने के बजाय इन नेताओं ने सद्भाव का नारा देते हुए उन्हें पटाने की कोशिश की। यह कोशिश कारगर रही, पर इस प्रयास के परिणामस्वरूप सवर्ण के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति का मतदाता भी कांग्रेस-इ की पकड़ से निकल गया।

निश्चित रूप से इन तिकड़मों के बावजूद पक्ष-विपक्ष के प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्रों में अपनी विजय अनिश्चित मानते थे। अनिश्चय की इस स्थिति में अलवर व सवाईमाधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान पक्ष-विपक्ष के समर्थकों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा किया और वहीं फर्जी मतदान का खासा जोर रहा। यह अलग बात है कि अनिश्चय की इस स्थिति के बावजूद भाजपा, जद तथा सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता प्रदेश की सभी २५ सीटों पर अपनी विजय की घोषणा करते रहे।

सत्ताधारी दल की पराजय का रहस्य: राजस्थान का सत्ताधारी दल दरअसल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी के अफलातूनी निर्णयों का शिकार हुआ है। मसलन प्रारंभ में 'मिस्टर क्लीन' ने अपने दल में सत्ता के दलालों अथवा बिगड़ी छवि के लोगों को अलग करने की मुहिम चलायी। इस मुहिम के तहत वरिष्ठ कहे जाने वाले कांग्रेसजनों को शक्तिविहीन बताया गया। संगठन के स्तर पर ताकत उन्हें सौंपी गयी जिन्हें राजीव गांधी अपनी तरह से साफ-सुथरा समझते थे। इस प्रक्रिया में हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया जैसे नेताओं को राज्यपाल बनाकर प्रदेश की राजनीति से बेदखल किया गया। संगठन में अशोक गहलोत के नेतृत्व में युवाओं का एक ऐसा समूह खड़ा हुआ जिसने प्रदेश में ब्लाक स्तर तक अपना कब्जा जमा लिया। फिर बोफोर्स के किस्से ने जब राजीव गांधी को पूरी तरह हिला दिया, तो तिकड़मी राजनीति के लिए पुरानों की वापसी का दौर चला। इस प्रयास के परिणामस्वरूप प्रदेश कांग्रेस ऐसे दोगले लोगों का जमघट बन गयी जिनका एक मात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना था।

इन स्थितियों में प्रदेश कांग्रेस-इ में एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी की पहली परिकल्पना के अनुसार पंचायत चुनावों व उप चुनावों में उपलब्धियां हासिल की थीं और दूसरी ओर वे लोग थे जो राजीव गांधी के राजीव सुधार कार्यक्रम से अपनी सारी प्रतिष्ठा खो चुके थे। बंटी हुई इस प्रदेश कांग्रेस को चुनाव वर्ष के नाम पर एक होकर कार्य करने को कहा तो गया, लेकिन विपरीत ध्रुवों पर बैठे लोगों की एकता संभव

नहीं हो सकी।

इसके अलावा युवाओं को शक्ति स्तंभ बनाने की घोषणा करने वाले राजीव गांधी ने प्रदेश के २५ लोकसभा प्रत्याशियों में जब जोधपुर व चुरु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत और नरेन्द्र बुढानिया को प्रत्याशी बनाया, तो जाने-पहचाने चेहरों और दलाली के प्रकरणों से ऊबे लोगों ने सरकार परिवर्तन के लिए मतदान करने में कोई हिचक नहीं दिखायी।

नतीजतन प्रदेश के ३५ हजार गांवों में जिला व ब्लाक स्तर से नीचे जाकर बनी कांग्रेस की ग्राम समितियां युवाओं की निष्क्रियता से कागजी बन कर रह गयीं। प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा इन्हें सक्रिय करने के बजाय इन्हें बदलने में जुटे रहे। नतीजा यह हुआ कि अपदस्थ लोग या तो बागी बन गये या फिर निष्क्रिय हो गये। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर केवल उन्हें मनाते रहे जिन्होंने कांग्रेस संगठन के साथ पंचायत चुनावों और उप-चुनावों में घात किया था।

इसके विपरीत विभाजित विपक्ष ने अपने राष्ट्रीय नेताओं के आदेशों के अनुसार भेदभाव भुलाकर चुनावी संघर्ष में एक दूसरे की मदद की। आश्चर्यजनक रूप से भाजपा को सांप्रदायिक करार देने वाले प्रदेश जद अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने चुनावी सघर्ष के दौरान अपना मुंह बंद रखा, वहीं भाजपा नेता भैरों सिंह शेखावत ने ईमानदारी से जद प्रत्याशियों की मदद की।

निश्चित रूप से विपक्ष की एकता के लिए भाजपा नेता भैरों सिंह शेखावत को श्रेय दिया जा सकता है। शेखावत क्षेत्र में मतदान के चार दिन पूर्व त्रिकोणात्मक संघर्ष को सीधे संघर्ष में बदलने के लिए जद प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटाने में कुटनीतिज्ञ सफलता भी हासिल की। जनता दल के साथ चुनावी एकता में शेखावत ने जद प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की भूमिका को बौना बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल का पूरा भरोसा हासिल किया। नतीजा यह हुआ कि सीटों के लेन-देन में शेखावत के सामने कोई समस्या नहीं रही।

चुनाव परिणाम : प्रदेश की सभी २५ सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार १४ सीटों पर लड़े और तेरह पर विजयी हुए। भाजपा के इन तेरह उम्मीदवारों में से आठ एक लाख से ज्यादा मतों से विजयी हुए हैं। सवाईमाधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस दल के डा० किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रामकुमार मीणा को एक लाख ९८ हजार १३५ मतों से पराजित किया। लोकसभा के चुनावों में राजस्थान में इस बार विजय का यह सर्वोच्च आंकड़ा है। जनता दल ने अपने हिस्से की बारह सीटों में से एक सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी। इस दल के सभी ग्यारह उम्मीदवार विजयी रहे। इस दल के सात उम्मीदवार एक लाख से ज्यादा मतों से विजयी रहे। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने अपने भतीजे केंद्रीय कपड़ा मंत्री रामनिवास मिर्धा को एक लाख ९० हजार २७० मतों से पराजित कर दल की ओर से सर्वाधिक मत हासिल किये।

बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक एवं प्रत्याशी श्योपत सिंह ने भाजपा के ओम प्रकाश आचार्य व कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद मनफूल सिंह भादू दोनों को पराजित किया। श्योपत सिंह ने २ लाख ९६ हजार ७१९ मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के मनफूल सिंह भादू को ६७ हजार ७७१ मतों से पराजित किया। सांसद मनफूल सिंह भादू को यहां २ लाख २८ हजार ९४८ मत प्राप्त हुए जबकि भाजपा प्रत्याशी को एक लाख आठ हजार ७३९ मतों से संतोष करना पड़ा। जनता दल में इस सीट को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दिये जाने पर गहरा असंतोष था और शुरू में समझा जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी मनफूल सिंह भादू यहां से आसानी से विजयी हो जायेंगे।

सिर मुंड़ाते ही ओले : दंगे में बदलता विजय जुलूस

जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजा और रंक की लड़ाई मतदान के दिन तक सेवक और सैनिक का चुनावी संघर्ष बन गया था। कांग्रेस के प्रत्याशी ले० कर्नल भवानी सिंह को शिकस्त देने के लिए भाजपा के उम्मीदवार विधायक गिरधारी लाल भार्गव के साथ भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के अलावा जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी सक्रिय थीं। चुनाव राजनीति से अनभिज्ञ पूर्व महाराजा भवानी सिंह को कांग्रेस के जिन जयपुरी नेताओं ने सहयोग दिया, उनकी छवि ऐसी नहीं थी कि वे मतदाताओं के बीच जाकर अपने उम्मीदवार की वकालत कर सकते। इनकी जनछवि का अहसास जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित सभा के दौरान हुआ। इस सभा को रात आठ बजे राजीव गांधी संबोधित करने वाले थे। एक लाख के आसपास सुनने वालों की इस सभा को जब जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश घीया ने संबोधित करने का प्रयास किया, तो लोगों ने उन्हें हूट कर दिया। राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष श्रीराम गोटेवाला ने अपना वाकचातुर्य प्रदर्शित करने की कोशिश की, तो सभा ने उन्हें घोटालेवाला कह कर विदा कर दिया। पूर्व विधायक जर्नादन सिंह जोशीली आवाज में कुछ कहने आये, तो जनता ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। इस पर नाराज नेता माइक से उपस्थित जनसमूह को भाजपाई करार देने लगे। पर इसी जनसमूह ने प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद दोनों हाथ उठाकर कांग्रेस को वोट देने की शपथ ली।

जनभावना को समझने से इनकार करने-वाले कांग्रेस प्रत्याशी ले०क० भवानी सिंह की हार के विशेष कारण बने। इन नेताओं के अधीन रहने वाले संगठनों ने न तो विधानसभा क्षेत्र में आम मतदाताओं से संपर्क किया और न ही पर्चियां बांटीं। कांग्रेसियों में मात्र जयपुर के विधायक शिवराम शर्मा के अलावा सारे नेता कार्यकर्ता दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर शर्मा की मदद के लिए चले गये। इन स्थितियों में ले० कर्नल भवानी सिंह को पूरी तरह अल्पसंख्यक समूह के कार्यकर्ताओं पर निर्भर होना पड़ा। परिणामस्वरूप भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को अल्पसंख्यकों का प्रत्याशी साबित करने में मतदाताओं के सामने कोई कठिनाई नहीं हुई।

ग्यारह लाख ३१ हजार ६४४ मतदाताओं

वाले जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पौने दो लाख के लगभग अल्पसंख्यक मतदाता जयपुर शहर के निवासी हैं। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र अल्पसंख्यकों ने शत प्रतिशत मतदान किया। यानी सात लाख २३ हजार ३७० मतदाताओं ने मतदान किया जिनमें तीन लाख ८४ हजार १२५ मत भाजपा प्रत्याशी गिरधारी लाल भार्गव को मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ले० कर्नल भवानी सिंह दो लाख ९९ हजार ६३८ मत ही प्राप्त कर सके।

जयपुर जिले के दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रं में कांग्रेस के जयपुर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नवल किशोर शर्मा प्रत्याशी थे। नवल किशोर शर्मा कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिन्हें राजीव गांधी ने रद्द करने के बाद पुनः चुनावी संघर्ष के लिए अपनी बगल में बिठाया था। पूर्व में तीन बार दौसा लोकसभा निर्वाचान क्षेत्र से निर्वाचित हुए इस सांसद ने पिछली बार जयपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार पुनः आलाकमान ने इन्हें चुनाव-मैदान में दौसा से उतारा और दौसा के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट को भारतपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने के लिए मजबूर किया। गुर्जर बहुल इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी विधायक नाथूसिंह गुर्जर थे। दस लाख तीस हजार २८३ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में पांच लाख ८३ हजार ६०९ मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें भाजपा प्रत्याशी को तीन लाख तीस हजार ७४९ मत प्राप्त हुए जबकि नवल किशोर शर्मा को दो लाख १३ हजार ८९९ मत ही प्राप्त हुए। इस तरह भाजपा प्रत्याशी नाथूसिंह ने एक लाख १६ हजार ८५० मतों से कांग्रेसी प्रत्याशी पर अपनी जीत दर्ज की।

इसी तरह राजस्थान के उदयपुर संभाग में लोकसभा की पांच सीटें आती हैं। विपक्ष के भाजपा घटक ने इस संभाग के लिए उदयपुर के पूर्व विवादास्पद महाराणा महेन्द्र सिंह से हाथ मिलाया। कांग्रेस की पिछले चुनावों में वकालत करने वाले महाराणा से भाजपा की अपेक्षा थी कि वे इस संभाग में अपने साथ भाजपा के बाकी दो उम्मीदवारों की भी मदद करेंगे। अपेक्षा के अनुरूप भाजपा का यह गठजोड़ विपक्ष के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। पूर्व महाराणा महेन्द्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला कुमारी शक्तावत को एक लाख ९१ हजार ७३८ मतों से पराजित किया। दस लाख २७ हजार १३७ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में ६ लाख ४३ हजार ७२८ मतदाताओं ने मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती शक्तावत को २ लाख पांच हजार ३१८ मत प्राप्त हुए जबकि महेन्द्र सिंह को तीन लाख ९७ हजार ५६ मत मिले।

इस मुकाबले की दिलचस्प बात यह रही कि महेन्द्र सिंह महाराणा प्रताप के वंशज हैं और मेवाड़ के अंतिम महाराणा दिवंगत भोपाल सिंह के पौत्र हैं। इनका मुकाबला करने वाली कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मला शक्तावत महाराणा प्रताप के अनुज शक्ति सिंह के वंशज ओछड़ी जागीर के अंतिम जागीरदार दिवंगत भोपाल सिंह की पौत्री हैं। इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि एक वक्त महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह आमने-सामने थे और इस बार उनके वंशज आमने-सामने रहे।

इसी संभाग की उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया का मुकाबला भाजपा के पूर्व विधायक गुलाबचंद कटारिया से रहा। उम्र के अंतिम पड़ाव में श्रीमती सुखाड़िया दुबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थीं, लेकिन गुटों में बंटी कांग्रेस के लिए दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। परिणामस्वरूप भाजपा के गुलाबचन्द कटारिया ने दस लाख २९ हजार ३६४ मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती सुखाड़िया को सूर्यवंशी महाराणा के प्रभाव से एक लाख तीस हजार पांच सौ दो मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव क्षेत्र में कुल मतदान ५ लाख ९७ हजार ७९२ मतदाताओं ने किया। श्रीमती सुखाड़िया को २ लाख ९ हजार १६३ मत हासिल हुए जबकि भाजपा प्रत्याशी कटारिया को तीन लाख ३९ हजार ६६५ मत मिले। इसी चुनाव क्षेत्र में राजस्थान की २५ सीटों पर चुनाव लड़ने वाली दूरदर्शी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम नारायण को १२ हजार ९१९ मत प्राप्त हुए।

बुलंदजीत : कल्याण सिंह कालवी

गुपचुप रणनीति : मिर्धा

इस संभाग की जन-जाति के लिए सुरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में भाजपा, कांग्रेस और माकपा में त्रिकोणात्मक संघर्ष था। यहां कुल मतदाता ९ लाख ११ हजार ४५७ थे जिनमें से मतदान में चार लाख ६६ हजार ३९७ ने हिस्सा लिया। भाजपा के उम्मीदवार पूर्व विधायक एवं मंत्री नन्दलाल मीणा, कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश के राज्य मंत्री भैंरूलाल मीणा को मात्र ८७८ मतों से पराजित कर विजयी रहे। उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी को दो लाख तीन हजार दस मत प्राप्त हुए। माकपा के उम्मीदवार मेघराज तावड़ को २१ हजार ८३७ और दूरदर्शी पार्टी के उम्मीदवार भूरा मीणा ने १८ हजार ८२५ मत हासिल किये। देश में लोकसभा के चुनावों में सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार शायद भाजपा के नन्दलाल मीणा ही हैं।

इसी संभाग की दूसरी जनजाति के लिए सुरक्षित बांसवाड़ा संसदीय सीट पर जद के प्रत्याशी हीराभाई ने कांग्रेसी प्रत्याशी को ९ हजार ३२५ मतों से परास्त किया। ९ लाख ३७ हजार ८९८ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में पांच लाख ४ हजार १०२ मतदाताओं ने मतदान किया। इन मतों में से जद के प्रत्याशी हीराभाई को दो लाख ९६ हजार ५९४ मत हासिल हुए जबकि पराजित प्रत्याशी को एक लाख ८७ हजार २६९ मत मिले। बांसवाड़ा असम के वर्तमान राज्यपाल हरिदेव जोशी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र रहा है। परमार को कांग्रेसी गुटबंदी के कारण इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। दूसरी ओर हीरा भाई के लिए आदिवासी क्षेत्र में लोकप्रिय मामा बालेश्वर ने विशाल सभाएं संबोधित कीं।

मेवाड़ की पकडवाली पांचवी सीट भीलवाडा से कांग्रेसी प्रत्याशी सांसद गिरधारी लाल व्यास तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के इस गृह जिले और निर्वाचन क्षेत्र में जद प्रत्याशी हेमेन्द्रसिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरधारी लाल व्यास को एक लाख ३२ हजार ९७ मतों से पराजित किया। नौ लाख ७३ हजार ४९७ मतदाताओं के इस चुनाव क्षेत्र में पांच लाख ३२ हजार ८४३ मतदाताओं ने मतदान किया। जद प्रत्याशी हेमेन्द्रसिंह को दो लाख ९० हजार ९५२ मत प्राप्त हुए जबकि कांग्रेसी प्रत्याशी गिरधारी लाल व्यास एक लाख ५८ हजार ८५५ मतों से आगे नहीं बढ़े। इस निर्वाचन क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक दंगों के दौरान कांग्रेस की भूमिका पर रोष प्रकट करते हुए अलग से अपना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया। उम्मीदवार शब्बीर हुसेन ने मुस्लिम मतदाताओं के २५ हजार ७२३ मत प्राप्त किये।

जोधपुर संभाग में जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य के गृहमंत्री एवं सांसद अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी थे। गहलोत को भाजपा के प्रत्याशी एवं राज्यसभा के सदस्य जसवंत सिंह ने सीधे मुकाबले में ६६ हजार २४६ मतों से हराया है। दस लाख ८३ हजार ५५७ मतदाताओं के इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल ६ लाख २ हजार ३६२ मतदाताओं ने मतदान किया।

PRATIBHA ZARDA
प्रतिमा
PRABHAT ZARDA
PRABHAT
ZAFRANI PATTI
IS 2344
RATNA BRAND
ZAFRANI PATTI
64
300
रत्नावली
ज़ाफरानी पत्ती
रत्ना
पान मसाला
Jai
ZAFRANI PATTI
जय
ज़ाफरानी पत्ती
दमकते प्रभात के
चमकते सितारे
राजरत्न
किवाम
TRADE MARK
REGD NO. 295532
PRIYA
ZAFRANI PATTI
FLAVOURED CHEWING TOBACCO FLAKES
प्रभात ज़र्दा उत्पादन
वैधानिक चेतावनी तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

भाजपा के विजयी उम्मीदवार जसवंत सिंह को दो लाख ९५ हजार '९९३ मत मिले जबकि कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार अशोक गहलोत को दो लाख २९ हजार ७४७ मत प्राप्त हुए।

अशोक गहलोत की पराजय निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा अपने निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल गनी खां सिंघी को समर्थन देने और वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्वारा घात करने से हुई है। अल्पसंख्यकों के तीस हजार ९६९ मत अब्दुल गनी खां सिंघी की झोली में चले गये, वहीं निर्णय बदलने की क्षमता रखने वाले जाट मत परसराम मदेरणा और उनके जिला प्रमुख पुत्र महिपाल मदेरणा की नाराजगी से गड़बड़ा गये। परिणामस्वरूप बेहतर टीम के बावजूद भी गहलोत पराजय के शिकार हुए।

पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गुमानमल लोढ़ा विजयी हुए। राजस्थान में रामशिला पूजन समारोह समिति के अध्यक्ष बने गुमानमल लोढ़ा इस चुनाव से पूर्व हुए उप-चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के हाथों पराजित हो चुके थे। पर वर्तमान चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कानूनविद लक्ष्मीमल सिंघवी को एक लाख ६७ हजार ३२८ मतों से पराजित किया। ९ लाख ५६ हजार ३८८ मतदाताओं वाले इस संसदीय क्षेत्र में कुल पांच लाख ४२ हजार २५६ मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। इन मतों में से गुमानमल लोढ़ा को तीन लाख ३८ हजार ७९७ मत प्राप्त हुए जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मीमल सिंघवी एक लाख ७१ हजार ४६९ मतों तक सीमित रहे। दूरदर्शी पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार को यहां पांच हजार ९८० मत प्राप्त हुए।

प्रदेश के जालौर (सु०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव घोषणा के एक माह पूर्व तक कांग्रेसी प्रत्याशी एवं केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह की ऐसी स्थिति थी कि चुनाव क्षेत्र में गये बगैर वे अपनी विजय की अपेक्षा करते, तो गलत न होता। केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों से चुने गये कांग्रेसी विधायक शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल में प्रभावी स्थान रखते थे। मसलन कैबिनेट मंत्री मांगीलाल आर्य और सूरजपाल सिंह मंत्रिमंडल में महज इसलिए सुरक्षित थे कि उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री के चुनाव क्षेत्र की देखभाल करनी होती थी। दस लाख ७६ हजार ९७५ मतदाताओं की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर अनुसूचित जाति और राजपूतों को मिला कर विजय का गठजोड़ बनता रहा है। पिछली बार केंद्रीय गृहमंत्री की जीत इसी गठजोड़ के कारण बड़ी सरल थी। बूटासिंह ने १९८४ में भाजपा के प्रत्याशी हुकमाराम मेघवाल के मुकाबले दो लाख ८१ हजार ६२७ मत प्राप्त किये थे और हुकमाराम मात्र एक लाख १८ हजार १६३ मत प्राप्त कर सके थे। इस बार भाजपा के विजयी प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक कैलाश मेघवाल ने कुल मतदान पांच लाख ९९ हजार १०७ में से तीन लाख ५१२ मत प्राप्त किये जबकि बूटासिंह को दो लाख ४७ हजार १०७ मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ५३ हजार ४०५ मतों की बढ़त से भाजपा प्रत्याशी ने केंद्रीय गृहमंत्री को शिकस्त दे दी।

सीधे मुकाबले में जीत: जसवंत सिंह

आम आदमी कीं जीत: गिरधारी लाल भार्गव

वैसे सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने इन चुनावों में हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल की हालत पतली कर दी थी। जद के प्रत्याशी के रूप में देवीलाल और कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में बलराम जाखड़ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में आमने-सामने थे जहां के ग्यारह लाख ३० हजार ९०८ मतदाताओं में से तीन लाख से ज्यादा मतदाता उनकी अपनी जाति के थे। सीकर शहर और उससे जुड़े अन्य कस्बे नीम के थाना में ब्राह्मण व वैश्य मतदाताओं का असरदार वोट था। भाजपा और माकपा के प्रभाव वाले इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इस तरह से बंटे थे कि वे एक साथ किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में नहीं जा सकते थे। पर इस बार दोनों विपक्षी दल देवीलाल के लिए प्रचार कर रहे थे। मतदान के दिन देवीलाल कैंप को गुमान हुआ कि सीकर और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी प्रत्याशी बलराम जाखड़ को ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं, तो स्थानीय भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी द्वारा बूथों पर कब्जे का सवाल खड़ा किया गया। दरअसल सीकर शहर के मतदाताओं के लिए यह संभव नहीं था कि वे उस प्रत्याशी को मत देते जिसकी वकालत माकपा के लोग कर रहे हों। यह बात चुनाव परिणामों के लिए हुई मतगणना के दौरान साबित हो गयी। कांग्रेस के प्रत्याशी को बढ़त केवल सीकर शहर और नीम का थाना के मतपत्रों की गणना के दौरान ही हासिल हुई। बहरहाल प्रतिष्ठा के इस चुनाव में जद के प्रत्याशी चौधरी देवीलाल को तीन लाख ७५ हजार ८५५ मत मिले जबकि कांग्रेसी प्रत्याशी बलराम जाखड को तीन लाख २९ हजार ९९ मत प्राप्त हुए और वे ४६ हजार ७५६ मतों से पराजित हो गये। इस

विपक्ष ने अपने राष्ट्रीय नेताओं के आदेशों के अनुसार भेदभाव भुलाकर चुनावी संघर्ष में एक दूसरे की मदद की। आश्चर्यजनक रूप से भाजपा को सांप्रदायिक करार देनेवाले प्रदेश जद अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने चुनावी संघर्ष के दौरान अपना मुंह बंद रखा, वहीं भाजपा नेता भैरोंसिंह शेखावत ने ईमानदारी से जद प्रत्याशियों की मदद की।

जनवरी प्रथम पक्ष
कढ़ाई/क्रोशिया
विशेषांक
आज ही अपनी प्रति
सुरक्षित कराइए

30 Gm
moov
moov
moov
moov
Ayurvedic Medicine
(AL USE ONLY)

जोड़ों का दर्द ख़ूब?

आराम दिलाए 'मूव'

घुटने के जोड़ का दर्द?
पीठ के जोड़ों का दर्द?

उम्र की वृद्धि से या अधिक कठिन परिश्रम करने से आपके शरीर के विभिन्न जोड़, विशिष्ट रूप से आपके घुटने और आपकी पीठ, दर्द के क्षेत्र बन जाते है. यह दर्द, जोड़ों के बीच में चिकने तरल की कमी से होता है. जोड़ों में रगड़ होने से आपको पीड़ा और बेचैनी होने लगती है.

जड़ तक पहुँचने वाला

'मूव' में है बहुत गाढ़े प्राकृतिक परिवर्तनशील तेल, जो आपकी त्वचा से होकर जोड़ों में दर्द की जड़ तक पहुँच जाते है

जल्द असर करने वाला

'मूव' अपने प्राकृतिक तेलों से – जो शक्तिदायक लाभकर रस है, तुरन्त ही रक्त का प्रवाह बढ़ाते है. चिकना तरल वापस आ जाता है. आपको मिलता है जल्द आराम.

अधिक समय तक आराम दिलाए

'मूव' के मलते ही, उसका बेजोड़ फार्मूला वाला बेस प्राकृतिक तेलों का स्थिर प्रवाह करता है, जो प्रभावित क्षेत्र को अधिक समय के लिए गर्म रखता है, बिना त्वचा को जलन पहुँचाते हुए.
दर्द बिना की गतिशीलता लौट आती है और आप फिर आराम से चल-फिर सकते है.

उत्तम निवारक, बेहद असरकारक

'मूव'

जोड़ों का दर्द निवारक

PARAS PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
Virendra Chambers, Ashram Road, AHMEDABAD 380 014

निर्वाचन क्षेत्र में सात लाख ३७ हजार ५१९ मतदाताओं ने मतदान किया।

भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश पायलट और टिकटों की लेन-देन के दौरान विचार बदलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले उनके मित्र जद के प्रत्याशी विश्वेन्द्रसिंह आमने-सामने थे। ९ लाख दो हजार ६८९ मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र से पायलट पूर्व में सांसद रह चुके हैं, पर इस बार जद प्रत्याशी के लिए स्थानीय लगाव ने पायलट को शिकस्त दे दी। निर्वाचन क्षेत्र में पांच लाख ९४ हजार २२३ मतदाताओं ने मतदान किया जिसमें जद विजयी प्रत्याशी विश्वेन्द्रसिंह को तीन लाख २३ हजार १७७ मत और कांग्रेसी प्रत्याशी राजेश पायलट को दो लाख ५२ हजार ७२२ मत मिले। इस तरह राजेश पायलट ७० हजार ४५२ मतों से पराजित हो गये।

चुरु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल के प्रत्याशी दौलत राम सारण ने कांग्रेस के नरेन्द्र बुढ़ानिया को एक लाख २४ हजार ६७० मंतों से पराजित किया। जद के वरिष्ठ नेता सारण को तीन लाख १८ हजार ९०७ मत प्राप्त हुए। दस लाख ४६ हजार ४६३ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में कुल छह लाख चार हजार ६५८ मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया।

झुंझुनूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के मोहम्मद अयूब खान को एक लाख ६१ हजार ९८१ मतों से पराजित किया। ग्यारह लाख २५ हजार ३५४ मतदाताओं वाले इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सात लाख तीस हजार २५९ मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। जनता दल के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ अपने प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा के बाद ऐसे दूसरे प्रत्याशी रहे हैं जिन्हें चार लाख से ज्यादा मत प्राप्त हुए। धनखड़ को कुल मतदान में से ४ लाख २१ हजार ४८६ मत प्राप्त हुए जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब खान को दो लाख ५९ हजार ७०५ मत मिले।

बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल के कल्याणसिंह कालवी ने कांग्रेस के वर्तमान सांसद बिरधीचन्द जैन को एक लाख ५७ हजार ४५५ मतों से पराजित किया। ग्यारह लाख सात हजार ३७१ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में कुल ६ लाख १० हजार ७१७ मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। जद के विजयी उम्मीदवार को तीन लाख ६७ हजार ५७० मत प्राप्त हुए जबकि पराजित उम्मीदवार को दो लाख दस हजार ११५ मत प्राप्त हुए।

श्रीगंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रहा है। दस लाख ८६ हजार ११८ मतदाताओं के इस निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के बेगाराम निर्वाचित हुए हैं। बेगाराम ने कांग्रेस के प्रत्याशी माथुर मंत्रिमंडल के खान राज्यमंत्री हीरालाल इंदौरा को ६३ हजार ५३३ मतों से पराजित किया। कुल मतदान किया पांच लाख ७६ हजार ५८० मतदाताओं ने जिनमें से तीन लाख सात हजार २७९ बेगाराम के पक्ष में गये और कांग्रेसी प्रत्याशी को दो लाख ४३ हजार ७४६ मत प्राप्त हुए।

रामशिलापूजन के सहारे जीत : लोढ़ा

नाथू सिंह

टौंक संसदीय (सु) निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के गोपाल पचेरवाल ने कांग्रेसी प्रत्याशी बनवारीलाल बैरवा को एक लाख सात हजार ९२९ मतों से पराजित किया। नौ लाख ८९ हजार १८३ मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल पांच लाख ४६ हजार ७२२ मतदाताओं ने मतदान किया। जद प्रत्याशी गोपाल पचेरवाल ने सन ८० व ८४ में चुने गये कांग्रेसी सांसद बनवारीलाल बैरवा के मुकाबले दो लाख ९४ हजार ६९७ मत प्राप्त किये जबकि बैरवा को कुल एक लाख ८६ हजार ७६८ मत प्राप्त हुए।

बयाना (सु) निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में आये भाजपा के थानसिंह ने कांग्रेसी प्रत्याशी श्रीमती शांति पहाड़िया को ६३ हजार १२८ मतों से परास्त किया। नौ लाख ४२ हजार ९९४ मतदाताओं वाले इस संसदीय क्षेत्र में चार लाख छह हजार ८२० मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा के विजयी प्रत्याशी को दो लाख १७ हजार ७०२ तथा कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार को एक लाख ५४ हजार ५७४ मत प्राप्त हुए।

अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जद के प्रत्याशी रामजीलाल यादव ने कांग्रेस के मौजूदा सांसद रामसिंह यादव को ८८ हजार ५१५ मतों से पराजित कर दिया। नौ लाख ५१ हजार ६८६ मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में चार लाख ६० हजार ६०६ मतदाताओं ने मतदान किया। जद के प्रत्याशी को मतदाताओं ने दो लाख ५२

ग्यारह लाख ३१ हजार ६४४ मतदाताओं वाले जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पौने दो लाख के लगभग अल्पसंख्यक मतदाता जयपुर शहर के निवासी हैं। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र अल्पसंख्यकों ने शत-प्रतिशत मतदान किया।

जनवरी प्रथम पक्ष
मनोरमा
कढ़ाई/क्रोशिया
विशेषांक
आज ही अपनी प्रति
सुरक्षित कराइए

स्पुतनिक

(अंतर्राष्ट्रीय मासिक)

सोवियत पत्रिकाएं
त्यौहार के
मौके पर
विशेष छूट

स्पुतनिक
स्पुतनिक
स्पुतनिक
स्पुतनिक

संसार की अनेक भाषाओं के साथ-साथ अब हिंदी में भी

सोवियत नीति, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, राष्ट्रीय गतिविधि और जनजीवन के विषय में विचारोत्तेजक, रोचक और ज्ञानवर्द्धक सामग्री एवं अपने मित्र-देश की अंतरंग झांकी

12 अंक मुफ्त 33% बचत कीजिए

विशेष छूट का लाभ उठाइये
तीन वर्ष के लिए चंदा भेजिए
और 33% की बचत कीजिए
12 अंक मुफ्त
रियायत साल के आखिर तक उपलब्ध

स्पुतनिक की प्रति आप अखबार के हॉकर से मंगा सकते हैं अथवा स्टॉल से खरीद सकते हैं।

एक प्रति का मूल्य 5 रुपये

व्यापारिक जानकारियों के लिए कृपया संपर्क करें

सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी
4 ई/4, झंडेवालान एक्सटेंशन नयी दिल्ली-110 055

"स्पुतनिक" के लिए डी डी/एम ओ प्रेषित है
तीन वर्ष का चन्दा 120 रुपये
एक वर्ष का चन्दा 60 रुपये
(अवांछनीय काट दीजिये)

नाम ______________________

पता ______________________

____

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
५-ई रानी झांसी रोड
नई दिल्ली-११००५५

मनीषा ग्रन्थालय (प्रा.) लि.
४/३, बी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-७०००७३

मैगज़ीन सेन्टर
एम.सी.डी. बिल्डिंग
नं. २, दूसरी मंजिल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
नई दिल्ली-११००५५

राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि.
चमेलीवाला मार्किट,
एम.आई.रोड, जयपुर-३०२००१

89

हजार ८२४ मत दिये जबकि लगातार दो बार कांग्रेसी सांसद रहे प्रत्याशी को एक लाख ६४ हजार ३०९ मत मिले।

सवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनजाति के लिए सुरक्षित सीट भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक डा० किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में रही। डा० मीणा ने दस लाख ३९ हजार ७२७ मतदाताओं वाली इस सीट को कांग्रेसी प्रत्याशी एवं सांसद रामकुमार मीणा से भारी संघर्ष के बाद हासिल की। प्रदेश में इसी सीट के मतदान केंद्रों पर कब्जे का सिलसिला चला। दुबारा मतदान हुआ और भाजपा प्रत्याशी ने प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजयी होने का कीर्तिमान स्थापित किया। डा० किरोड़ी लाल मीणा ने कुल पांच लाख ८५ हजार ६७९ मतदान में से तीन लाख ७४ हजार ६०१ मत प्राप्त कर कांग्रेसी प्रत्याशी को एक लाख ९८ हजार १३३ मतों से पराजित किया। कांग्रेसी प्रत्याशी को मात्र एक लाख ७६ हजार ४६८ मत प्राप्त हुए।

अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के रासासिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी एवं राज्य के वनमंत्री गोविन्द सिंह गुर्जर को एक लाख अस्सी हजार उन्तालीस मतों से पराजित किया। नौ लाख ३१ हजार ८०२ मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में पांच लाख ५५ हजार ७३१ मतदाताओं ने मतदान किया। विजयी प्रत्याशी को तीन लाख साठ हजार २५४ मत प्राप्त हुए जबकि पराजित उम्मीदवार को दो लाख दो सौ पंद्रह मत ही मिल पाये।

कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक दंगों और भाजपा के गढ़ के रूप में विख्यात है। नौ लाख ४२ हजार ४०९ मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में पांच लाख ४६ हजार ७२२ मतदाताओं ने मतदान किया। भाजपा के प्रत्याशी एवं विधायक दाऊदयाल जोशी ने मौजूदा कांग्रेसी सांसद शांति धारीवाल को एक लाख २८ हजार ६४० मतों से पराजित कर विजयश्री हासिल की। भाजपा प्रत्याशी को तीन लाख १४ हजार १३५ मत प्राप्त हुए जबकि कांग्रेसी सांसद एक लाख ८५ हजार ४९५ मतों पर ठहर गये।

झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक एवं ग्वालियर राजपरिवार की वसुंधरा राजे कांग्रेसी प्रत्याशी शिवनारायण का मुकाबला कर रही थीं। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेसी प्रत्याशी को एक लाख ४६ हजार ५४१ मतों से पराजित कर दिया। आठ लाख ९० हजार ७४९ मतदाताओं के इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल पांच लाख १४ हजार ३३६ मतदाताओं ने मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी को तीन लाख चार हजार ७२८ मत मिले जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र एक लाख ५८ हजार १८७ मत प्राप्त हुए।

नतीजों के परिणाम क्या होंगे?: राजस्थान के मुख्यमंत्री नतीजों को देखकर हक्के बक्के हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे हारे कैसे। वे केवल इतना भर कहते हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। पर इस बदलाव का कारण उनकी समझ में नहीं आता। वे अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनने बैठ जाते हैं। सूखे, अकाल और प्रदेश के विकास में कांग्रेस के रोल की चर्चा करते हैं। बहरहाल चुनाव परिणामों का फल यह हुआ कि मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से हाथ धोना पड़ा।

वसुंधरा राजे

गुलाब सिंह कटारिया

इसके विपरीत भाजपा एवं प्रदेश के नेता भैरोंसिंह शेखावत विपक्ष की विजय को जनता द्वारा विपक्ष को स्वीकारने की सनद मानते हैं। वे नहीं मानते कि रामशिला पूजन का कोई प्रभाव प्रदेश के मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाला रहा है। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रामशिला पूजन को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। वे बड़े भोलेपन से सवाल पेश करते हैं कि 'हम राम और रहीम को राजनीति में कैसे डाल सकते हैं?"

उधर लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय के बाद राज्य सरकार के गृहमंत्री पद से त्याग पत्र देकर अलग हुए अशोक गहलोत इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर रोष प्रकट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में हिन्दूवाद को उभारा और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यकों को भड़का कर गुमराह किया है।

इन बयानों के अतिरिक्त प्रदेश में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं वहां विजयी जुलूसों में अल्पसंख्यकों को भड़काने वाले नारे लगाये जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के इस रवैये का नतीजा है कि सद्भाव के लिए मशहूर जयपुर शहर में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति भाजपा के विजय जुलूस के साथ भड़की आग से नष्ट हो गयी। जयपुर शहर सेना और कर्फ्यू के संरक्षण में सांस लेने लगा था। विजय जुलूस जनता दल के भी निकले हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे हादसे पेश नहीं आये।

—ओम सैनी

शक्ति प्रदर्शन के रवैये का नतीजा है कि सद्भाव के लिए मशहूर जयपुर शहर में करोड़ों रुपयों की संपत्ति भाजपा के विजय जुलूस के साथ भड़की आग से नष्ट हो गयी। जयपुर शहर सेना और कर्फ्यू के संरक्षण में सांस लेने लगा था। विजय जुलूस जनता दल के भी निकले हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे हादसे पेश नहीं आये।

जनवरी प्रथम पक्ष
मनोरमा
कढ़ाई/क्रोशिया
विशेषांक
आज ही अपनी प्रति
सुरक्षित कराइए

नये चेहरे क्या गुल खिलायेंगे ?

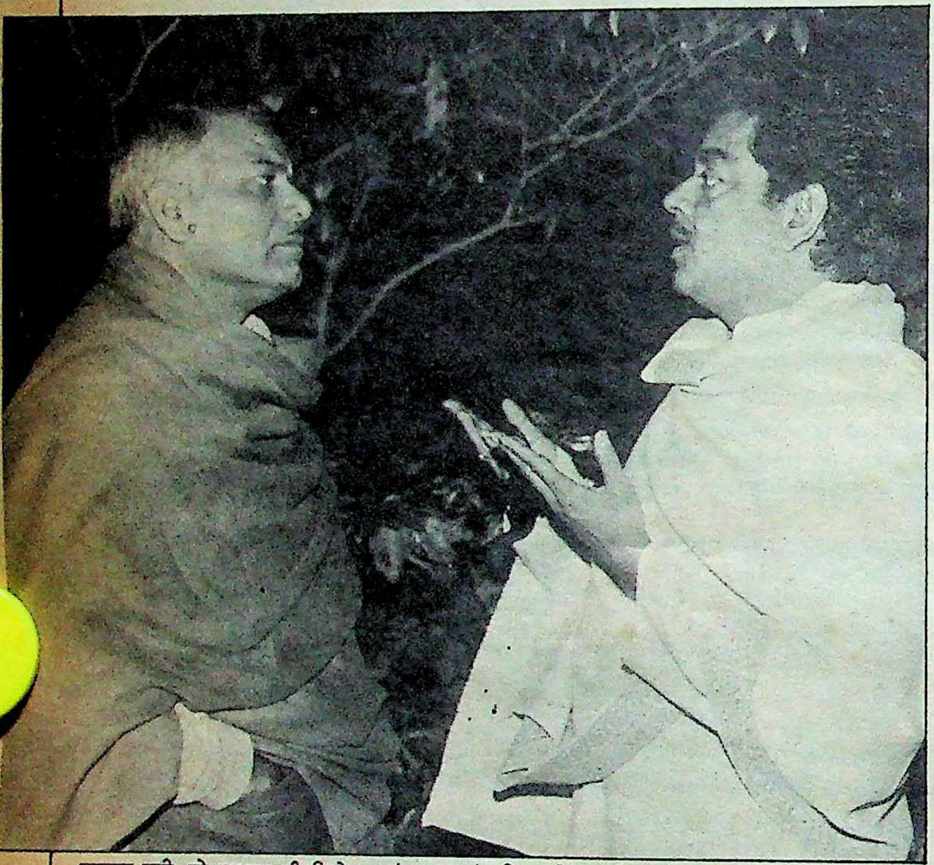

जरूरत पड़ी, तो आपका भी विरोध करूंगा : यशवंत सिन्हा से मुखातिब शत्रुघ्न सिन्हा

संसद भवन के सुरक्षाकर्मियों की जान सांसत में है। नवीं लोकसभा में ३७१ नये चेहरे चुनकर आ गये हैं जिनमें से अधिसंख्य को सुरक्षाकर्मी पहचानते तो क्या, उनका नाम तक नहीं जानते हैं। उन्हें यह भय बना हुआ है कि कहीं अनजाने में किसी से कोई बदसलूकी न हो जाये। कारण, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे का नेता चुने जाने के दिन से ही संसद भवन के प्रवेश द्वार पर उनके समर्थकों, प्रशंसकों और तमाशबीनों की जो भीड़ जमा है, वह गुंजाइश होते ही सदन के परिसर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है। उस अफरातफरी के बीच फंसे नवनिर्वाचित सांसद अपना परिचय बताते, भीड़ से बचते-बचाते प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। हालांकि आननफानन नये सांसदों को अस्थायी पास जारी करने के लिए स्वागत कक्ष में ही लोकसभा के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। इनके लिए फौरी तौर पर आवास की व्यवस्था भी करने की भागदौड़ चल रही है।

अपनी-अपनी दौड़ : और दो चार दिनों में यह भागदौड़ थम जायेगी और राजनीति के नये मोहरे अपनी-अपनी चालें खेलने लगेंगे। इनमें से कौन कितनी दूर दौड़ कर जायेगा यह बात भविष्य के गर्भ में है, पर इतना तो तय है कि लगभग एक दर्जन नये संसद सदस्य भारतीय राजनीतिक पटल पर धूमकेतु की तरह उभरेंगे। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो चुनाव नहीं लड़े हैं और कुछ चुनाव में हार गये हैं, पर इससे उनकी राजनीतिक हैसियत में फर्क नहीं पड़ा है और वे पूरे ठसके से अपनी भूमिका निभाने को तत्पर हैं। इनमें प्रमुख हैं राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा और राजमोहन गांधी।

जनता दल के लिए धुआंधार प्रचार करने में राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ने ही कोई कसर नहीं उठा रखी। अपने भाषणों में कांग्रेस और राजीव गांधी पर जितने तीखे प्रहार राज बब्बर ने किये, शत्रुघ्न उतने ही चुटीले भाषणों की समा बांधते रहे। राज बब्बर तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव से हैं। इलाहाबाद में राजा के 'ऐश महल' में ही डेरा डालकर बब्बर ने यमुना पार के देहाती इलाकों की बहुत धूल फांकी थी। इतनी लंबी मशक्कत के बावजूद पहली दिसंबर को, जब राजा नेता चुने जा रहे थे, संसद भवन के द्वारपालों ने उन्हें अंदर घुसने से मना कर दिया और वे अन्दर जाने के लिए नारे लगाते पत्रकारों-फोटोग्राफरों के साथ खड़े रहे। बहुत जोर-आजमाइश के बाद सेंट्रल हाल के अंदर जाकर देखा, तो शत्रुघ्न सिन्हा सामने राजा के बगल में विराजमान थे। राज बब्बर को पीछे पत्रकार-सांसद संतोष भारतीय के पास बैठने की जगह मिल सकी। पत्रकार कयास लगा रहे थे कि इन दो फिल्मी सिपहसालारों में एक को राज सिंहासन के निकट और दूसरे को दूर क्यों रखा गया? क्या शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक हैसियत बब्बर से ज्यादा है? राज बब्बर से पूछने पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, "शत्रुघ्न सिन्हा नेता हैं और मैं कार्यकर्ता।" वास्तविकता यह है कि इन दोनों फिल्म अभिनेताओं में से कोई भी राजीव गांधी के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का अमिताभ बच्चन नहीं बन सकेगा—कारण, राजा की राजनीतिक मान्यताएं व मर्यादाएं अलग हैं। लेकिन ये दोनों ही नयी सरकार के बहुत निकट और असरदार व्यक्तित्व बने रहेंगे।

अपने को 'असली गांधी' कहने वाले राजमोहन गांधी हालांकि अमेठी संसदीय क्षेत्र से राजीव गांधी से चुनाव हार गये हैं, पर इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ है। महात्मा गांधी का यह पोता पहली बार चुनाव मैदान में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में उतरा—वह भी उत्तर प्रदेश के सबसे कठिन निर्वाचन क्षेत्र से। अपनी पराजय को झाड़-पोंछकर गांधी जब दूरदर्शन पर साक्षात्कार दे रहे थे, तब उन्होंने जिस विश्वास के साथ सूचना प्रसारण विभाग और दूरदर्शन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल की बात की, उससे स्पष्ट है कि नयी सरकार में उनका पूरा दखल रहेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपने लायक आधा दर्जन मंत्रालय गिना डाले जिन्हें अगर प्रस्ताव आता है, तो वे संभालना चाहेंगे। वैसे राजनीतिक क्षेत्र में जोरदार चर्चा है कि राजमोहन गांधी को कोई मंत्रालय सौंपा जा सकता है—यदि तुरंत नहीं, तो कुछ दिन बाद। जाहिर है, नयी सरकार इस पत्रकार-इतिहासकार

की काबिलीयत का पूरा फायदा उठाना चाहेगी।

राजनीतिक क्षितिज पर जो नये (निर्वाचित) सितारे उभरे हैं, उनमें मेनका गांधी, पत्रकार संतोष भारतीय (संपादक 'चौथी दुनिया') व अजय सिंह (संपादक 'असली भारत'), पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री, बिहार के तेजतर्रार युवा नेता रामविलास पासवान, सुबोध कान्त सहाय और छेदी पासवान आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका पिछले चुनाव में राजीव गांधी के विरुद्ध अमेठी से चुनाव लड़कर हारी थीं, पर इस बार पीलीभीत से भारी बहुमत से जीतकर संसद में पहुंची हैं तथा नये मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री की शपथ ले चुकी हैं।

पत्रकारों को महत्व: उत्तर प्रदेश से लोकसभा में पहुंचे पत्रकारद्वय संतोष भारतीय और अजय सिंह प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निकट माने जाते हैं, जिनमें भारतीय को फर्रुखाबाद से टिकट दिलाने में सिंह को अपने कुछ साथी नेताओं की नाराजगी तक झेलनी पड़ी थी। इसी सीट से जद के दूसरे दावेदार सुधीन्द्र भदौरिया को राज्य सभा में पहुंचाने का वायदा कर ही भारतीय की उम्मीदवारी को पक्का किया गया था। भारतीय और अजय सिंह को सरकार में शामिल किये जाने की चर्चा है, पर बताया जाता है कि भारतीय स्वयं इसके विरुद्ध हैं। वे महसूस करते हैं कि अगर राजा साहब ने उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो उन्हें (प्रधानमंत्री) परेशानी उठानी पड़ सकती है। अजय सिंह को सरकार में शामिल किये जाने की अटकलें राजधानी से प्रकाशित होने वाले कुछ समाचारपत्रों द्वारा लगायी जा रही हैं और अजय ने इससे इनकार भी नहीं किया है।

बड़ी कंपनी की मोटे वेतन वाली जमी-जमाई नौकरी छोड़कर जद के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने और विजयी होने वाले अनिल शास्त्री कंपनी प्रबंध में अपनी लंबी पारी के कारण महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक बड़े (हरिकिशन शास्त्री) और छोटे (सुनील शास्त्री) भाई के दूसरे खेमे (कांग्रेस) में होने से अनिल के 'शास्त्री' होने का फायदा जद पूरी तरह उठायेगा और इसीलिए यदि सरकार में नहीं, तो पार्टी के संगठन स्तर पर या किसी सरकारी निगम या प्रतिष्ठान में उन्हें महत्वपूर्ण पद दिये जाने की चर्चा है।

बिहार से चुनकर आये रामविलास पासवान, सुबोध कांत सहाय—शैलेंद्र श्रीवास्तव और छेदी पासवान सरीखे तेजतर्रार नेताओं में हालांकि रामविलास पासवान का यह पहला संसदीय कार्यकाल नहीं है, पर उनका महत्व इस बार जितना बढ़ा है, वह आने वाले दिनों में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उनकी राजनीतिक हैसियत का प्रतीक है। सर्वाधिक मतों से अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर गिनीज बुक में दर्ज अपना ही रिकार्ड तोड़ने वाले पासवान मंत्रिमंडल में आ ही गये हैं और यह भी आशा की जा रही है कि छेदी पासवान, शैलेन्द्र श्रीवास्तव और सहाय का दबदबा केंद्र और राज्य स्तर पर बढ़ेगा।

नयी ऊष्मा: जहां एक ओर युवा चेहरे नयी ऊष्मा के साथ संसद भवन में पहुंचे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मदनलाल खुराना जैसे अनुभवी दिग्गज नेता भी पहली बार निर्वाचित हुए हैं। नयी सरकार के एक बाजू के रूप में भाजपा ने अपनी अपरिहार्यता तो स्पष्ट कर ही दी है, आडवाणी और खुराना सदन में अपनी राजनीतिक परिपक्वता का भी पूरा परिचय देंगे। सरकारी विधेयकों को पारित कराने में भाजपा की भूमिका बहुत निर्णायक होगी और निचले सदन में उनका अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

मैं कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं: राज बब्बर बीपी सिंह के पुत्र अजेय सिंह से हाथ मिलाते हुए

पंजाब से एकीकृत अकाली दल (मान) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान, विमल खालसा और अतिन्दरपाल सिंह समेत कुल छह सदस्यों का भारी बहुमत से जीतकर लोकसभा में पहुंचना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। पिछली सरकार द्वारा आतंकवादी करार दिये गये ये लोग अपनी निजी निष्ठा और मान्यताएं लेकर संसद में पहुंचे हैं। पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं से निपटने में इस शक्तिशाली राजनीतिक गुट का नयी सरकार को पूरा सहयोग लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने पहले प्रसारण में कहा था कि 'घाव संगीनों से नहीं सिये जा सकते हैं, उन पर मरहम लगाने की आवश्यकता है।'

इन सबसे अलग पहली बार एक कट्टर धार्मिक नेता महन्त अवैद्यनाथ गोरखपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर दिल्ली पहुंच गये हैं। महंत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और बिना हिचक हिंदू कार्ड खेलकर चुनाव जीते हैं।

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस चुनाव में ढाई दर्जन से अधिक दिग्गज कांग्रेसी नेता धूल चाट गये हैं। इनमें लगभग दो दर्जन केंद्रीय मंत्री और पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं। केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह, मोहसिना किदवई, जेड ए अंसारी, रामनिवास मिर्धा, राजेश पायलट, जगदीश टाइटलर, नटवर सिंह, बी के गढ़वी, डूमरलाल बैठा, कृष्णा शाही और गैर मंत्री नेताओं में नरेश चंद्र चतुर्वेदी, नवल किशोर शर्मा, योगेंद्र मकवाना, ममता बनर्जी, अशोक गहलौत, दिग्विजय सिंह सरीखे नेता विपक्ष में बैठने लायक भी साबित नहीं हुए। आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ को उनके रिश्ते के साले चौधरी देवीलाल ने ही पटकनी लगाकर चित्त कर दिया। पार्टी की हार के बावजूद कांग्रेसी नेता हताश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अभी यह आशा है कि वाम और दक्षिणपंथियों के सहारे बनी सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पायेगी और उन्हें लौटकर सत्ता संभालनी है। उनका भविष्य नयी सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर टिका है।

छाया: मनमोहन शर्मा

—बिशन कुमार

राष्ट्रीय सरकार की खिचड़ी क्यों नहीं पकी ?

"यह एक कठिन और साथ ही बहुत बड़ा कार्य है कि ऐसी राष्ट्रीय सरकार गठित कर ली जाये जो सभी दलों का समर्थन पाये और काम करे।" यह कहते हैं भाजपा नेता अटलबिहारी वाजपेयी।

"राष्ट्र के सामने जटिल समस्याएं खड़ी हैं, वह टकराव झेलने की स्थिति में नहीं है। आपस में समन्वय कायम करना ही होगा। (प्रस्तावित) राष्ट्रीय सरकार किसी भी पार्टी को अलग नहीं रहने दे सकती, कांग्रेस-इ को भी नहीं। लेकिन यह बात संदेहास्पद है कि कांग्रेस-इ इस तरह की सरकार में शामिल होगी।" कहते हैं जनता दल नेता चंद्रशेखर। और कांग्रेस-इ प्रस्तावित राष्ट्रीय सहमति की सरकार में शामिल होगी या नहीं, इस पर पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी का कहना है, "हमने अभी ऐसी कोई योजनां देखी नहीं है। मुझसे इस संबंध में संपर्क भी नहीं किया गया है। ऐसे में मैं क्या कह सकता हूं?"

बताया जाता है कि २६ नवंबर की शाम राष्ट्रीय सहमति की सरकार की योजना लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलनेवाले अज्ञात बुद्धिजीवियों की चाल लगभग कामयाब हो चली थी। लेकिन उनकी योजना को कम्युनिस्टों ने एक बारगी नामंजूर कर दिया। कांग्रेस-इ के प्रवक्ता आनंद शर्मा इस योजना को बिना समझे ही जरूरत से ज्यादा चौकस हो गये और विरोधाभासी रुख अपनाते हुए बोले, "हमारी पार्टी सर्वदलीय सरकार बनाने की किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करती, लेकिन यदि ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की ओर से आये, तो उस पर विचार करेगी।" मतलब यह कि ऐसी राष्ट्रीय सरकार में सिर्फ राष्ट्रीय मोरचा और भाजपा के लोग होते। दूसरे शब्दों में यह राष्ट्रीय स्तर पर हरिणाला-शैली की साझा सरकार होती है। मंत्रिमंडल वस्तुतः जनता दल का होता, पर उसमें भाजपा भी शरीक होती। मजे की बात यह है कि कोई भी नेता उन बुद्धिजीवियों का हुलिया बताना नहीं चाहता, जबकि माना यह जाता है कि उक्त बुद्धिजीवियों ने अधिकतर बड़े नेताओं से संपर्क साधा था। तो क्या वे कुछ ऐसे लोग थे, जिनमें महत्वाकांक्षा जग गयी थी और जो यह समझ रहे थे कि त्रिशंकु की तरह लटकी संसद और तात्कालिक अनिश्चितता के कारण जनता दल राष्ट्रीय सरकार बनाने को राजी हो जायेगा? कुछ भी हो, जैसे ही जनता दल के नेताओं को भनक लगी कि इस योजना के पीछे कुछ और ही मंशा है, वे उस प्रस्ताव के प्रति उदासीन और अनिच्छुक हो गये। अकेले चंद्रशेखर ऐसे नेता थे जो इस विचार से चिपके रहे। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी सरकार के नेता वीपी सिंह तब तक नहीं हो सकते, जब तक सांप्रदायिकता और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर खुलेआम समझौता नहीं कर लेते। यह विचार देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने की चंद्रशेखर की योजना के भी अनुकूल था। संभवतः भाजपा भी पहले से ही यह आस लगाये बैठी थी कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में साझा सरकार बनने से उसके कम-से-कम तीन नेताओं—अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और विजयराजे सिंधिया—को मंत्रिमंडल में रखा जायेगा। संयोग से देवीलाल से तीनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं।

भाजपा का नया शिगूफा : अटल बिहारी वाजपेयी

भाजपा और क्या करती ? : हरकिशन सिंह सुरजीत

लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि वीपी सिंह ऐसी किसी भी साझा सरकार के खिलाफ हैं, जिसमें भाजपा की शिरकत हो और कम्युनिस्टों की नहीं, यह योजना टांयटांय फिस हो गयी। आखिरी कोशिश के तौर पर भाजपा ने पहले से रखी जाती रही अपनी यह शर्त भी छोड़ी कि जिस सरकार में कम्युनिस्ट होंगे, उसमें वह शामिल नहीं होगी। भाजपा नेताओं के लिए यह एक साहसपूर्ण निर्णय था, क्योंकि पार्टी के लोग नेतृत्व पर सत्ता में भागीदारी के लिए पार्टी नीति के खिलाफ समझौता करने का आरोप लगाते। लेकिन कम्युनिस्ट ऐसी किसी सरकार में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, जिसमें भाजपा और कांग्रेस-इ में से कोई भी शामिल हो और कम्युनिस्टों के अभाव में लोकसभा में भाजपा-राष्ट्रीय मोरचा गठबंधन का बहुमत ही नहीं बनता। ऐसी परिस्थिति में भाजपा चाहती थी कि कांग्रेस-इ राष्ट्रीय सरकार में शामिल हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

भाजपा के परिपक्व नेता अटलबिहारी वाजपेयी सवेरे-सवेरे तुरुप की एक चाल चले थे। योजना का पूरे हृदय से समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहमति की सरकार में कांग्रेस-इ की शिरकत पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते उससे राजीव गांधी को अलग रखा जाये। जब यह जिक्र इंका प्रवक्ता आनंद शर्मा से किया गया, तो वे चिढ़ गये और प्रस्ताव को एकबारगी नकार गये। शर्मा अगर दूसरी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते, तो अनुशासनहीनता के आधार पर पार्टी से अपने निष्कासन को ही आमंत्रित करते।

ऐसे में भाजपा के लिए एक यही विकल्प रह गया कि वह प्रस्तावित सरकार का नेतृत्व कांग्रेस-इ को देने की पहलकदमी दिखाये। लेकिन ऐसा होने पर राष्ट्रीय मोरचा और वाममोर्चा दोनों योजना को ठुकरा देते। कुल मिलाकर वह कांग्रेस-इ की ही साझा सरकार होती, जिसमें थोड़ी-सी हिस्सेदारी भाजपा की होती। इस गठजोड़ को लोकसभा में २७७ सांसदों का समर्थन प्राप्त था। साथ ही सहयोगी दलों के १६ सांसद—अद्रमुक ११, शिवसेना ४, नेशनल कांफ्रेंस ३, हिंदूमहासभा १—भी समर्थन देते। लेकिन तब भाजपा की स्थिति दयनीय हो जाती। कारण, उस पर यह आरोप चस्पा हो जाता कि वह जनादेश के प्रति मगरूरी बरत रही है और कांग्रेस-इ को फिर सत्ता में ला रही है। इससे भाजपा, गैरकांग्रेस-इ विपक्ष से कट कर पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाती, यानी उसे हल्के और फौरी फायदे के लिए भारी और दीर्घकालिक मूल्य चुकाना पड़ता। इससे भी बढ़कर, पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाने का डर था।

दोतरफा खतरे की इसी हालत में भाजपा ने राष्ट्रीय मोरचा सरकार को 'गुण-दोष के आधार पर किंतु बिना शर्त समर्थन' देने का फैसला किया। माकपा पोलितब्यूरो के सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत का कहना है, "भाजपा के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था।" और इसके साथ ही राष्ट्रीय सहमति की सरकार का सपना टूट गया। लोकसभा में मात्र १४१ सीट पानेवाला राष्ट्रीय मोरचा सरकार बनाने में सफल हो गया। मंत्रिमंडल में एक भी कुरसी पाये बगैर भाजपा को इस सरकार का समर्थन करना पड़ा। सदन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस-इ को विपक्ष की बेंचों पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा।

यह स्पष्ट रूप से वीपी सिंह के नैतिक पक्ष की विजय और राष्ट्रीय सहमति की आड़ में सत्ता चाहनेवालों की हार थी। वीपी सिंह ने संसद के सेंट्रल हाल में अपने पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, "राष्ट्रीय समन्वय का आशय मेरे लिए यह है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति का स्वागत किया जायेगा।" इस बयान ने सबको चुप और सारी अटकलों को खतम कर दिया।

—अभय अग्रवाल

लबिहारी
चले थे।
ए उन्होंने
कांग्रेस-इ
है, बशर्ते
। जब यह
गया, तो
गी नकार
ा जाहिर
र पार्टी से
ति।
ी विकल्प
का नेतृत्व
े। लेकिन
वाममोर्चा
नाकर वह
ी, जिसमें
ती। इस
का समर्थन
सांसद—
कांफ्रेंस ३,
किन तब
ारण, उस
जनादेश के
इ को फिर
रकांग्रेस-इ
थलग पड़
दे के लिए
पड़ता।
ी जाने का

भाजपा ने
के आधार
ला किया।
शन सिंह
नए दूसरा
साथ ही
टूट गया।
राष्ट्रीय
हो गया।
ाजपा को
सदन की
बेंचों पर

तिक पक्ष
ड़ में सत्ता
संसद के
कहा था,
यह है कि
हमति का
सबको चुप
या।
अग्रवाल

हीरो होन्डा के सवार के लिए
यह है बस एक लीटर की मार

हम यह बात ज़रा भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहे। अगर आप हीरो होन्डा सी डी 100 पर सवार हैं तो एक लीटर पेट्रोल आपको बहुत दूर—80 किलोमीटर दूर तक—ले जाएगा।

एक लीटर में आपको *इतनी* दूर भला और कौन सी मोटरसाइकिल ले जाएगी?

टैंक भरिए, और चलते चलिए.
होन्डा की तकनीकी श्रेष्ठता हीरो होन्डा सी डी 100 के असाधारण 4-स्ट्रोक इंजन की हर विशेषता में देखी जा सकती है। ईंधन पूरी मात्रा में जलने के कारण देखभाल में आसानी, 80 किलोमीटर प्रति लीटर* चलने की कुशलता, और साथ में प्रदूषणहीन एग्ज़ास्ट सुनिश्चित हैं—मीलों मील बिना-परेशानी अच्छी सेवा के लिए।

हां, हीरो होन्डा को लाखों ने अपनाया है। उन्हीं ने इसे भारत की सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिल बनाया है।

HERO
HONDA

आपका शानदार हमसफ़र!

* 40 कि.मी. प्रति घंटा और 130 किलो भार सहित.

HTA 6347 H

"फर्नेस में बिना किसी परिवर्तन के इस्पात निर्माण में दुगनी वृद्धि।"

श्री राजेश्वर सिंह, डिविजनल मैनेजर, एस एम एस-३ का विश्वास है कि उन्होंने अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा, साथ ही उनके विचार से, प्रत्येक भारतीय उद्योग को शायद इससे सबक मिले।

आज, टाटा स्टील ने अपने स्टील मेल्टिंग शॉप नं.३ में कई मार्गदर्शी कदम उठाये हैं, जैसे पुराने फर्नेसों (अधिक ऊर्जा खर्च करने वाले) को रद्द करना—जो कि एक बड़ा मुश्किल व खर्चीला काम है। टाटा स्टील ने कॉर्फ तकनीक चालू करके अपनी पुरानी धमन भट्टियों में सफलतापूर्वक हीट टाइम को ९-१० से ४ घंटे तक कम किया। इसलिये निर्धारित ईंधन खर्च में सीधे ५०% कमी हो गई।

ऊर्जा की भारी बचत के लिये टाटा स्टील ने एक अहम कदम उठाया, कॉन्कास्ट तकनीक को अपनाकर हीटिंग और रोलिंग के एक स्तर पर ईंधन खर्च समाप्त कर दिया। टाटा स्टील का लक्ष्य है कुछ ही वर्षों में निरंतर कास्टिंग (कॉन्कास्ट) पद्धति से ४००% की वृद्धि करना— जिससे भारी परिमाण में ऊर्जा की बचत होगी।

एल डी प्रक्रिया शुरू होने से फर्नेस की लाइनिंग को बदलना पड़ा। गैस एनलाइज़र के प्रयोग सहित उन्नत उपकरणों का उपयोग,सभी हरेक स्तर पर बेहतर ऊर्जा बचत की निश्चयता प्रदान करते हैं।

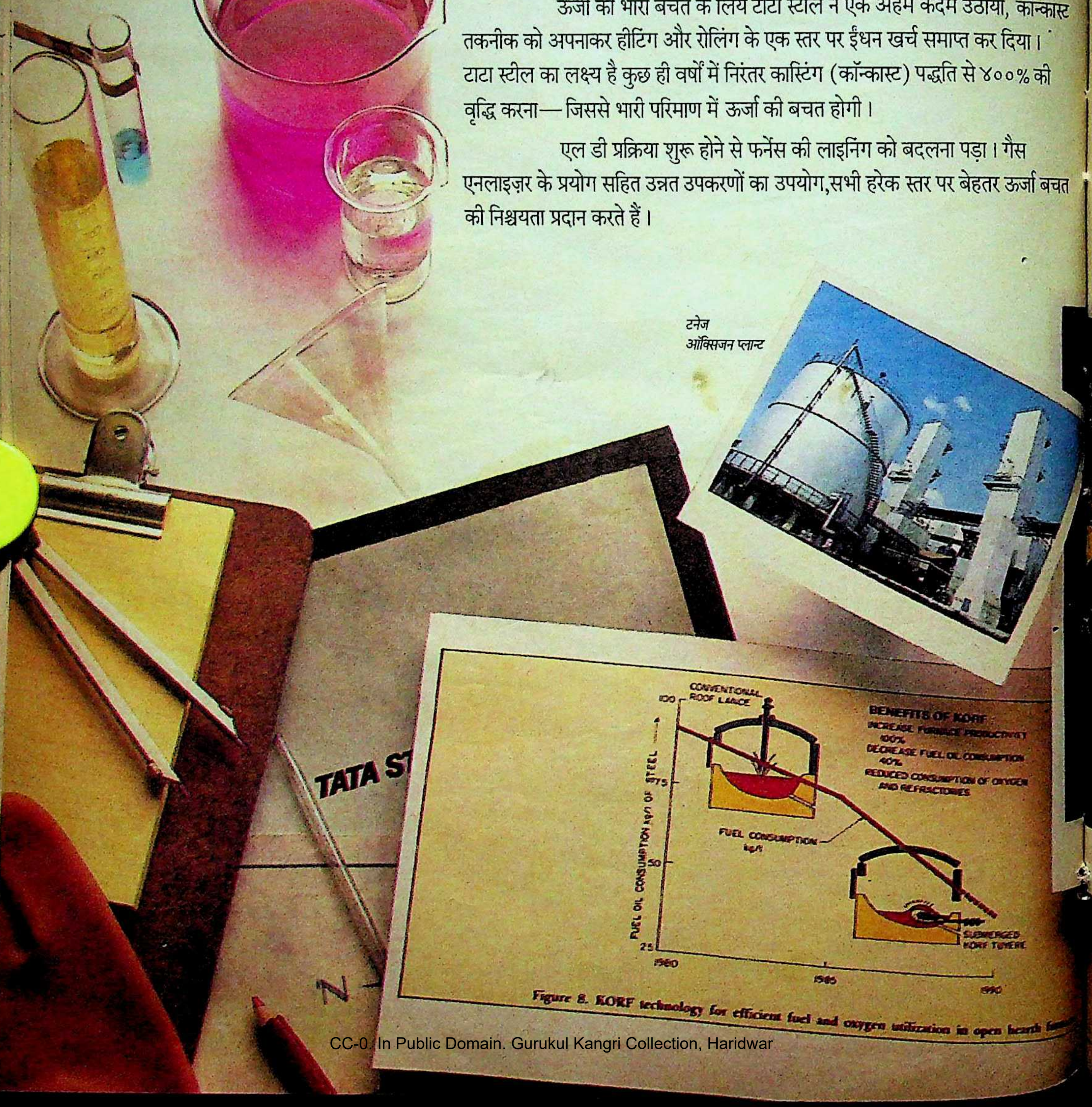
टनेज
ऑक्सिजन प्लान्ट
TATA ST
CONVENTIONAL ROOF LANCE
100
75
50
25
FUEL OIL CONSUMPTION kg/t OF STEEL
FUEL CONSUMPTION kg/t
BENEFITS OF KORF :
INCREASE FURNACE PRODUCTIVITY 100%
DECREASE FUEL OIL CONSUMPTION 40%
REDUCED CONSUMPTION OF OXYGEN AND REFRACTORIES
SUBMERGED KORF TUYERE
1980
1985
1990
Figure 8. KORF technology for efficient fuel and oxygen utilization in open hearth

द्ध।"
छ सीखा,
कदम
क एक बड़ा
ी धमन
निर्धारित
कॉन्कास्ट
या।
% की
स
र्जा बचत

सिर्फ कच्चे माल से इस्पात निर्माण तक ही नहीं, आज टिस्टेक के प्रत्येक स्तर पर कारगर ऊर्जा प्रबन्धन कार्यक्रम कमाल दिखा रहा है। कोक के लिये स्टैम्प चार्जिंग, ब्लू डस्ट से सिन्टर का निर्माण, रद्द किये गये मालों से बिजली और स्लैग से सिमेन्ट उत्पादन हो रहा है। एल डी टॉप गैस से फर्नेस रीहीटिंग आदि की तालिका दिन-ब-दिन लम्बी होती जा रही है।

TISTECH ENERGY

टिस्टेक का ऊर्जा कार्यक्रम सिर्फ प्रत्येक मशीन को ही नहीं, प्रत्येक मन को भी इसमें शामिल कर रहा है। टिस्टेक लोगों को सचेत और अग्रणी बना रहा है। अब टाटा स्टील का प्रत्येक कर्मी सिर्फ ऊर्जा संरक्षण की चर्चा ही नहीं करता बल्कि इसके बारे में कुछ न कुछ ठोस काम अवश्य कर रहा है।

टिस्टेक ऊर्जा—स्टील प्लान्टों के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक मार्गदर्शक प्रयास—जिसका लक्ष्य है एक प्रासंगिक तकनीक का उद्भावन, एक आधुनिक प्रगतिशील धारणा का प्रसारण। आने वाले कल के प्रयोजन को न भूल कर आज के जमाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के वायदों का एक और नाम — टिस्टेक!

- **ईंधन-तेल खर्च में ४०% की कटौती।**
- **प्रति वर्ष एल डी टॉप गैस से ४.५ करोड़ Nm³ की वसूली।**
- **कॉर्फ तकनीक के प्रयोग से ओपन हर्थ फर्नेसों में हीट वर्किंग समय आधा हुआ।**
- **ऊर्जा संरक्षण के लिये बार एण्ड रॉड मिल में फ्लैट फ्लेम बर्नर का इस्तेमाल शुरू।**

टाटा स्टील
सबसे पहले सबसे आगे

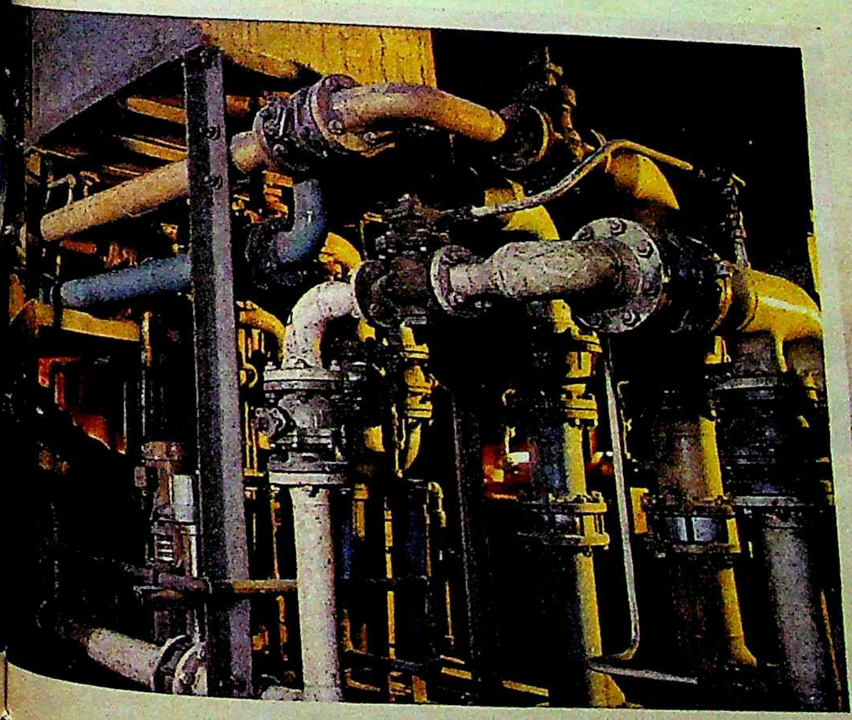

एस एम एस-३ में
कॉर्फ कन्ट्रोल पैनल

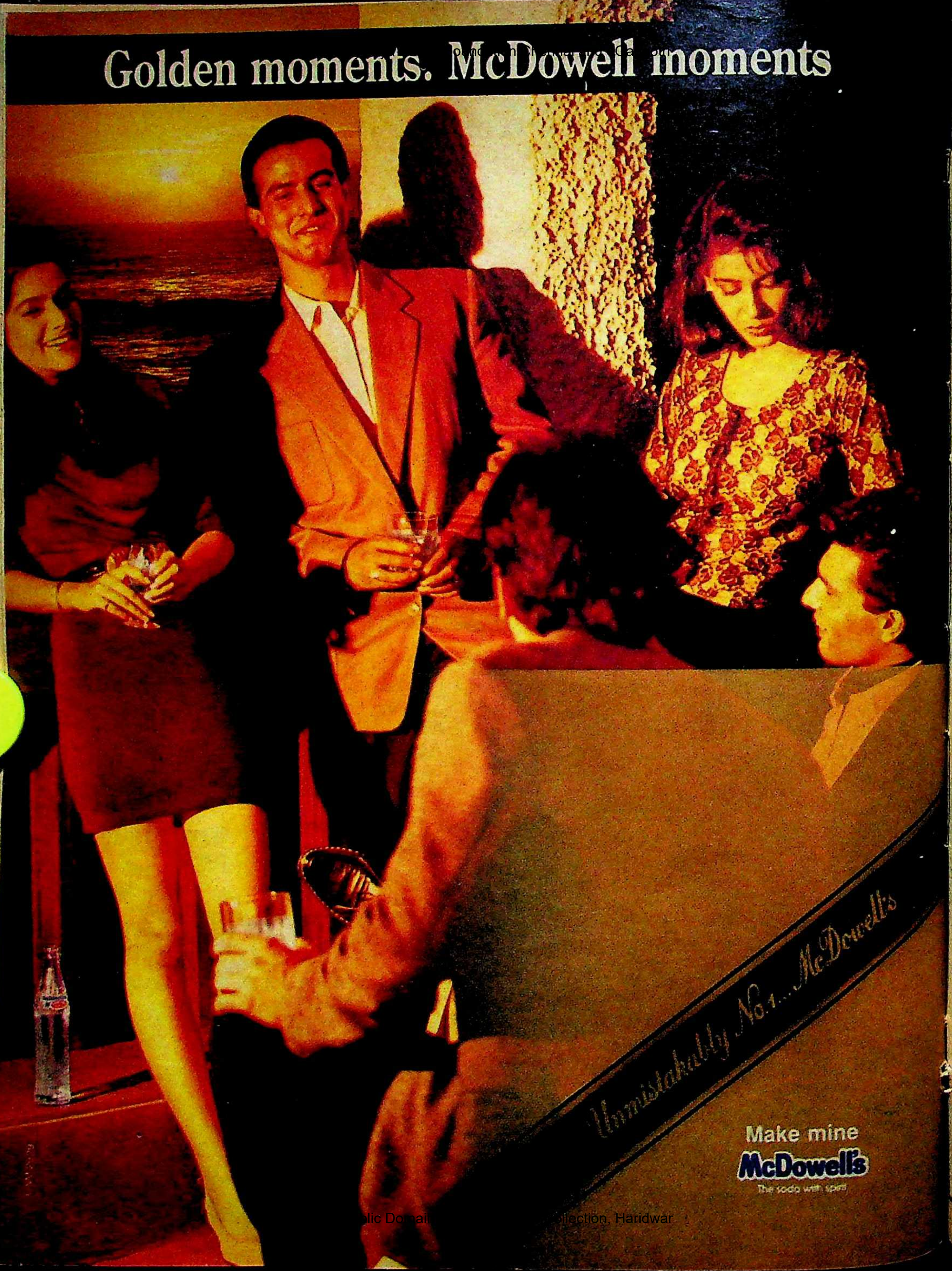
Golden moments. McDowell moments
Unmistakably No.1...McDowell's
Make mine
McDowell's
The soda with spirit

lic Domai ollection, Haridwar

देश

१५ नवंबर: बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष ५५ वर्षीय शिवनंदन पासवान् का निधन। जनता दल से निष्कासित नेता हरिकेश बहादुर कांग्रेस-इ में शामिल।

१६ नवंबर: हरियाणा में केआर पूनिया, हरि सिंह सैनी, लक्ष्मण सिंह कंबोज द्वारा देवीलाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा।

१७ नवंबर: हरियाणा के वन मंत्री परमानंद द्वारा देवीलाल मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। बंबई सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन में आग लग जाने से १८ व्यक्ति घायल।

१८ नवंबर: निर्दलीय प्रत्याशी सकटू सिंह की हत्या के कारण उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव स्थगित।

१९ नवंबर: प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा स्व० इंदिराजी के जन्म के अवसर पर कांग्रेस-इ मुख्यालय पर महिलाओं की भलाई के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की 'इंदिरा महिला योजना' का ऐलान।

२० नवंबर: जनता पार्टी के उम्मीदवार फतेह सिंह की मृत्यु से उप्र में चांदपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित।

२१ नवंबर: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबा साहब भोंसले द्वारा कांग्रेस-इ की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।

२२ नवंबर: अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल नेता संजय सिंह पर विरोधी दलों द्वारा गोलियों से जानलेवा हमला। श्रीमती पुपुल जयकर द्वारा प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार पद से इस्तीफा।

२३ नवंबर: निर्वाचन आयोग द्वारा ५७८ मतदान केंद्र पर पुनः मतदान कराने के आदेश।

२४ नवंबर: फतेहपुर में चुनाव के दौरान जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जान लेवा हमला। निर्वाचन आयोग द्वारा ८० संसदीय क्षेत्रों के ९३० मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान के आदेश।

२५ नवंबर: अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा ९७ मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराने के आदेश।

२६ नवंबर: हिंदी फिल्म अभिनेत्री चांद उस्मानी का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पडरौना कांग्रेस-इ लोकसभा सदस्य सीपीएन सिंह की जमीन के विवाद में हत्या। मुख्य चुनाव अधिकारी सतीश भटनागर द्वारा बिहार में ११२ मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराने के आदेश।

२७ नवंबर: प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति आर वेंकटरमण द्वारा लोकसभा भंग। राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक, मप्र के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा द्वारा प्रदेश में पार्टी की पराजय के कारण इस्तीफा।

२८ नवंबर: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव द्वारा राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में पार्टी की पराजय के कारण इस्तीफा।

२९ नवंबर: उप्र के राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ द्वारा विधान सभा भंग। सिक्किम संग्राम परिषद के अध्यक्ष नरबहादुर भंडारी सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता और पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित।

३० नवंबर: कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ। मप्र सरकार द्वारा वर्ष १९८९ का 'लता मंगेशकर पुरस्कार' सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले को देने की घोषणा।

संजय सिंह

आशा भोंसले

राष्ट्रपति इरशाद

कराजोन एक्विनो

विदेश

१५ नवंबर: नैरोबी में एक बस के नदी में गिर जाने से ५४ व्यक्तियों की मृत्यु।

१६ नवंबर: श्रीलंका सरकार द्वारा जनता विमुक्ति पेरामुना के उग्रवादियों से अपने हथियार सौंपने और हिंसक कार्रवाई बंद करने की अपील।

१७ नवंबर: पाकिस्तान के लाहौर जिले में एक बम विस्फोट में १५ व्यक्तियों की मृत्यु।

१८ नवंबर: यूगोस्लाविया में एक खान में आग लग जाने से ९४ व्यक्तियों की मौत।

१९ नवंबर: पूर्वी जर्मनी की सरकार द्वारा एक करोड़ लोगों को पश्चिमी जर्मनी जाने का वीसा।

२० नवंबर: कराची में भारत और पाकिस्तान के मध्य पहला टेस्ट क्रिकेट मैच बिना हार-जीत के समाप्त।

२१ नवंबर: चेकोस्लाविया में दो लाख लोगों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिलोस जैक्स के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विशाल प्रदर्शन। देश के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सेनो फोन्तास जोलोटास को यूनान का नया प्रधानमंत्री बनाने का फैसला। एन जैकोव मास्को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पद से हटे, बोरिस यन, येल्तसिन मास्को कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव नियुक्त।

२२ नवंबर: सोवियत संघ का एक यात्री विमान साइबेरिया में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त, ३४ लोग मृत। लेबनान के नये राष्ट्रपति रेने मोआवाद अपने आठ अंगरक्षकों समेत कार बम धमाके में मृत। सल्वाडोर में गुरिल्लों द्वारा बंधक बनाये गये अमरीकी सैनिक रिहा। पोलैंड की अनीता फ्रेगालिका को 'मिस वर्ल्ड' का खिताब।

२३ नवंबर: सोवियत संघ द्वारा प्रमुख भारतीय राजनयिक टीएन कौल 'आर्डर आफ पीपुल्स फ्रेंडशिप' पुरस्कार से सम्मानित।

२४ नवंबर: श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में जनता विमुक्ति पेरामुना की हिंसा में ४० व्यक्ति मृत, कैंडी क्षेत्र से ४० युवकों की लाशें बरामद। एलियस हावी लेबनान के दसवें राष्ट्रपति निर्वाचित।

२५ नवंबर: चेकोस्लाविया कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मिलोस जेक्स द्वारा इस्तीफा, पोलित ब्यूरो के सदस्य करेल उरबैनक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नियुक्त।

२६ नवंबर: सलीम हांस लेबनान के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।

२७ नवंबर: कोलंबिया का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, १०० यात्रियों की मृत्यु। उरुग्वे में सत्तारूढ़ पार्टी 'कोलरैडो' के सदस्य आम चुनाव में पराजित। लुइस अलबर्टो लैकाल उरुग्वे के नये राष्ट्रपति। कोमोरास द्वीप के राष्ट्रपति ७० वर्षीय हमीद अब्दुल्ला अंगरक्षक समेत सेना के दंगे में मृत।

२८ नवंबर: भारत और पाकिस्तान के मध्य फैसलाबाद में दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच अनिर्णीत।

२९ नवंबर: पाकिस्तान में संयुक्त विपक्षी दलो द्वारा राष्ट्रीय असेंबली में बेनजीर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने का फैसला। बांग्लादेश में विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति इरशाद के इस्तीफे की मांग को लेकर बंद का आह्वान, बंद के दौरान १०० व्यक्ति हताहत, पुलिस द्वारा ३५ व्यक्ति गिरफ्तार।

३० नवंबर: फिलीपींस में दंगाई सैनिकों द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों की घेराबंदी, राष्ट्रपति श्रीमती कराजोन एक्वीनो की सरकार को गिराने का असफल प्रयास।

यों लड़ी गयी चुनावी जंग !

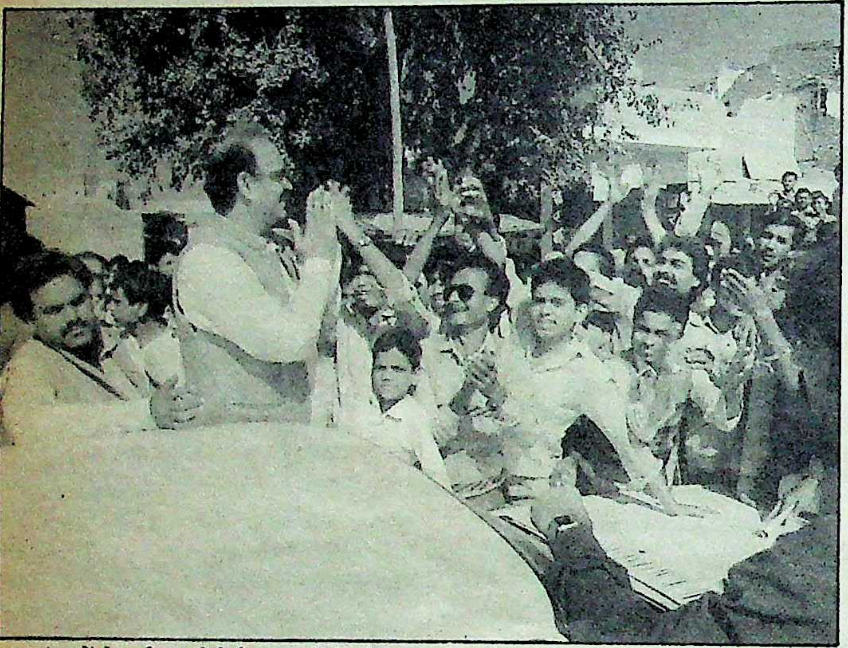

युवाकांक्षाओं के प्रतीक: वीपी सिंह युवकों के बीच

छाया: मनमोहन शर्मा

इस चुनावी दंगल के परिणाम कितने अपेक्षित और अप्रत्याशित रहे यह तो एक अलग हिसाब है, परंतु जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, वह पूरी तरह अपेक्षित था। चुनाव घोषणा पूर्व की सभी आशंकाएं कि चुनाव सर्वाधिक हिंसक और खर्चीला होगा—सही साबित हुईं। इसमें बहा खून देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक रिकार्ड रहा। हिंसा अपने पूरे ताण्डव पर रही। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में उत्पन्न खूनी माहौल में संपन्न १९८४ के चुनाव में केवल ४० व्यक्ति मृत्यु के घाट उतरे थे। लेकिन इस बार चुनाव घोषणा के दिन से चुनाव प्रचार समाप्त होने तक ही २३ लोग हिंसक राजनीति की बलि चढ़ चुके थे। मतदान के पहले चरण यानी २२ नवंबर तक २० जानें और गयीं और २४ व २६ का मतदान पूरा होने तक १५० से अधिक लोग रक्तिम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के शिकार बन गये।

गौरतलब है कि ये आंकड़े वे हैं जो समाचारपत्रों के जरिये आम जनता तक पहुंच पाते हैं। न जाने कितनी हिंसक वारदात की रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। सचाई यह है कि हथियारबंद गुटों की झड़पों, मारपीट, आगजनी और मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के प्रयासों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इस बार इनमें कितनी वृद्धि हुई है, यह इसी बात से जाहिर है कि विभिन्न देशव्यापी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश देने पड़े हैं, जोकि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। और-तो-और, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी तक में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सौ से अधिक मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की शिकायतें मिलीं और गोलियों की बौछार में फंसे प्रधानमंत्री के एक समय के करीबी, अब उप्र जनता दल महामंत्री व अमेठी विधानसभा क्षेत्र के जद उम्मीदवार, डा० संजय सिंह अस्पताल में पड़े जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। खूनी नाटक के अगले अंक में अमेठी संसदीय क्षेत्र के दूसरे 'गांधी' (राज मोहन) यहां की गड़बड़ियों के विरोध में हर लोकतांत्रिक संस्था के दरवाजे खटखटाते रहे।

अमेठी में हुई हिंसा पर पूरे देश में व्यापक और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यहां तक कि इससे क्षुब्ध होकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ बरसों तक जुड़ी रहीं पुपुल जयकर ने सांस्कृतिक सलाहकार पद से त्यागपत्र तक दे दिया। राष्ट्रपति आर वेंकटरमण को चुनाव आयोग से मामले की जांच करने की सिफारिश करनी पड़ी। यह हिंसा का ही परिणाम था कि जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मतदान मात्र दो प्रतिशत हुआ।

धन के परनाले: यदि इंसान का खून सस्ता रहा, तो चुनाव बहुत महंगा। जीतने की होड़ में तिजोरियों के मुंह खोल दिये गये। धन्ना सेठों ने थैलियां खोलीं—प्रत्याशियों को अपनी जेब में रखने के लिए, तो प्रत्याशियों ने वोट खरीदने के लिए। इस खरीद-फरोख्त में पक्ष या विपक्ष किसी को भी अस्पृश्य नहीं समझा गया। दोनों पालों में, पार्टी और प्रत्याशी के कद और हैसियत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाया गया। राजनीतिक क्षेत्रों में आम चर्चा है कि उद्योगपति अंबानी ने २०० करोड़ रुपए से कांग्रेस का कोष भरा, तो २० करोड़ से ऊपर विपक्ष की झोली में 'इंश्योरेंस' के तौर पर डाले। फर्क सिर्फ यह रहा कि कांग्रेस को यह राशि पार्टी कोष में दी गयी, जबकि विपक्षी खेमे में चुनिंदा प्रत्याशियों को।

छाया : राजीव कुमार

रस्मी जन-संपर्क: चुनाव अभियान पर राजीव गांधी

जिस देश में ५०,००० करोड़ रुपए से अधिक कालाधन अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो, वहां

सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस चुनाव में दस हजार करोड़ रुपए की आहुति दी गयी। उल्लेखनीय है कि यह राशि इतनी अधिक है कि इससे इस वर्ष का बजट घाटा पूरा किया जा सकता था।

कांग्रेस के एक उच्च पदाधिकारी से 'माया' ने जब यह सवाल पूछा कि लोकसभा और विधानसभा सीट पर कितना खर्च हो रहा है, तो उन्होंने बेधड़क कहा कि लोकसभा क्षेत्र में ५० हजार और विधानसभा क्षेत्र में २५ हजार। संवाददाता ने जब यह कहा कि कदाचित आपका आशय ५० लाख और २५ लाख से होगा, तो उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को ५ लाख रुपए से अधिक नहीं दिये गये हैं। पहली किस्त में तीन लाख रुपए ही बांटे गये थे। इनके बयान में कितनी सचाई है, इसका जायजा बंगलौर की विधानसभा की एक सीट् के प्रत्याशी के खर्च से लगाया जा सकता है। उनका चुनाव संचालन कर रहे एक सज्जन ने बताया कि चुनाव-प्रचार के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने प्रतिदिन एक से डेढ़ लाख रुपए का भुगतान अपने हाथों से किया। प्रचार का अंतिम चरण आते-आते यह राशि बढ़कर दो लाख रुपए तक जा पहुंची।

चुनाव प्रचार में सर्वाधिक खर्च वाहनों को जुटाने और उनके ईंधन पर हुआ। हालांकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता बताते हैं कि हर संसदीय उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से तीन से पांच जीपें उपलब्ध करायी गयीं। लेकिन वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक संसदीय क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के लिए ४०-५० वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह थी कि इससे भी कहीं बड़ी संख्या में वाहन हर क्षेत्र में जोते गये। चर्चा है कि केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और केंद्रीय राज्यमंत्री राजेश पायलट के क्षेत्र में ४०० से ५०० गाड़ियां मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में दौड़ती दिखायी दीं। स्वयं प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में स्थिति कुछ भिन्न न थी।

आम वाहन आम प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किये गये, तो बड़े नेताओं ने अत्याधुनिक रथों का उपयोग किया। यदि प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की स्वीकृति के साथ हवाई जहाज से दौरे करते रहे, तो हरियाणा के चौधरी देवीलाल, आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव और प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने हेलीकाप्टर का भी इस्तेमाल किया। मतदाताओं को लुभाने के समस्त हथकंडों से लैस प्रचार कार्य में ५० रथ लगे रहे। देवीलाल अपने 'विजय रथ' पर, फतह के लिए निकले, तो आंध्रप्रदेश में रामाराव 'चैतन्य रथ' पर, कर्नाटक में देवेगौड़ा अपने सुसज्जित रथ पर, हैदराबाद में ओवैसी अपने विलायती 'शाहीन रथ' पर, उप्र में जद नेता मुलायम सिंह यादव 'क्रांति रथ' पर और बूटा सिंह अपने निराले रथ पर जनता जनार्दन का हृदय जीतने निकले।

अभूतपूर्व प्रचार शैली: वाहनों के अतिरिक्त प्रेस विज्ञापनों, पोस्टरों, पर्चों, बैनरों आदि पर अपार धन खर्च हुआ। इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ते इस लोकतंत्र की चुनावी भूमि पर प्रचार के आधुनिक और आयातित साधनों—आडियो और वीडियो कैसेट—और उनको जनता के बीच पहुंचा कर सुनाने-दिखाने वाले वाहन ऐसे खर्चीले उपकरण हैं, जिनका इस्तेमाल इस चुनाव में अत्यधिक व्यापक स्तर पर हुआ। अनुमान है कि अकेले कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक प्रचार-प्रसार में ५०० करोड़ रुपए खर्च किये। उम्मीदवारों ने निजी स्तर पर अपने क्षेत्रों में चुनाव अभियान में जो खर्च किया, उसका हिसाब-किताब अलग है। कांग्रेस ने अपने मुद्दे मतदाता तक पहुंचाने के लिए एक माह से देश के तमाम समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये जिन पर लगभग दो सौ करोड़ रुपए खर्च किये जाने की बात है। यह कुव्यवस्था का द्योतक रहा या सामग्री की बहुतायत का कि राजस्थान में कांग्रेस के पोस्टरों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की प्रचार सामग्री छपी। इसी प्रकार कांग्रेस की नाक अमेठी में पार्टी के झंडे का हरा भाग काट जनता दल का झंडा बनाकर बड़ी तादाद में स्थानीय तथा पास पड़ोस के क्षेत्रों में बेचा गया।

इसके उलट, विपक्ष के पास साधनों की कमी को मद्देनजर रख जनता दल के लिए एक आडियो कैसेट फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने बंबई से बनवाकर दिया। जद प्रवक्ता यशवंत सिन्हा के अनुसार पार्टी ने कोई वीडियो कैसे नहीं बनवाया, जो कुछ कैसेट दिखायी दिये वे नेताओं ने व्यक्तिगत स्तर पर बनवाये। इनमें वीडियो का सर्वाधिक इस्तेमाल देवीलाल और एनटी रामाराव ने किया। आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपने एक मित्र की मदद से उपलब्ध कतरनों के जरिए तैयार वीडियो द्वारा अपने कार्यों और उपलब्धियों के जरिए अपने क्षेत्र में दर्शाया। अजीत सिंह ने चौधरी चरण सिंह पर भी फिल्म दिखाकर अपने पिता का नाम और काम भुनाया। भाजपा ने दो वीडियो कैसेट बनवाये। एक में जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरे में अपनी उपलब्धियां दिखायीं। व्यंग्यपूर्ण नुक्कड़ नाटकों के जरिए राज बब्बर ने जनता दल प्रत्याशियों के समर्थन में घमासान प्रचार कार्य किया। भाजपा और वामपंथी दलों ने भी नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने निराले चटपटे संवादों से विपक्षी प्रचार सभाओं में अभूतपूर्व समां बांध दिया।

इन अत्याधुनिक चुनाव हथियारों के बावजूद असली जंग देश की गलियों, नुक्कड़ों और चौराहों पर लड़ी गयी। यहां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया। एक ओर अगर गाली-गलौज का निम्न स्तर रहा, तो दूसरी तरफ वायदों की बुलंदियां रहीं। यदि प्रधानमंत्री और उनकी चौकड़ी पर भ्रष्ट, चोर

जन-जन से अपील: लालकृष्ण आडवाणी

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

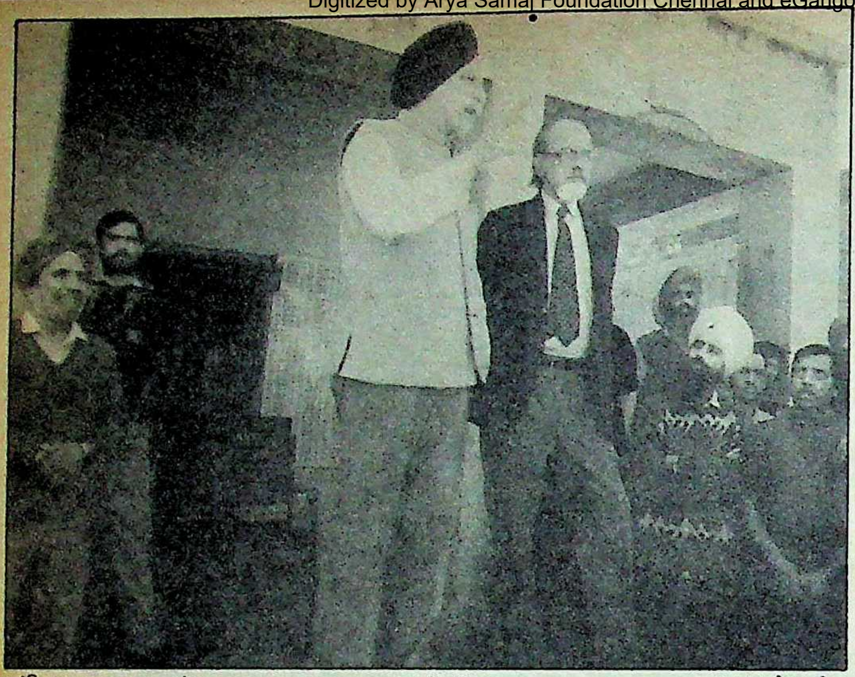

शांति का आश्वासन : इंद्र कुमार गुजराल चुनाव-सभा के दौरान

छाया : सुनील सक्सेना

और अनैतिक होने के आरोप लगे, तो देवीलाल हेगड़े और रामाराव के साथ ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी नहीं बख्शा गया। चुनाव के पहले से ही तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाने की जैसे होड़ लग गयी। चुनाव-प्रचार के दौरान ऐसा लगता था कि एक पक्ष ने अगर एक मुद्दा उठाया, तो उसका जवाब तुरत-फुरत दूसरे खेमे में आ गया।

दिलचस्प तथ्य यह कि दोनों खेमों ने अपना प्रचार नकारात्मक रखा। विपक्ष अगर सरकार की नाकामियों और निकम्मेपन को उधाड़ने पर तुला हुआ था, तो कांग्रेस विपक्ष की पिछली विफलता, फूट और स्थायी सरकार देने की अक्षमता को दर्शा कर जनता को आतंकित करती रही। कांग्रेस की प्रचार कमान संभालने वाले भारी-भरकम सांसद विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह के अनुसार चुनाव माहौल इतना विषाक्त हो गया कि पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंद्वी की नजर से नहीं, वरन दुश्मन मानकर प्रहार किये। जवाबी हमलों का आलम यह था कि कांग्रेस द्वारा बहुप्रचारित स्थिर सरकार बनाम खिचड़ी सरकार के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने कहा, “स्वस्थ व्यक्ति को अगर खिचड़ी के आहार पर रख दिया जाये, तो उसका कमजोर होना लाजिमी है। यही १९७७ में हुआ था। इस बार तो खिचड़ी १५ दलों की है।” जवाब जनता दल महासचिव अजीत सिंह ने दिया, “बीमारी के बाद खिचड़ी ही स्वास्थ्य लाभ की अचूक दवा होती है। १९७७ में इमरजेंसी के रोग से देश पीड़ित था, तो इस बार भ्रष्टाचार के रोग से। यह अलग बात है कि विदेशी तौर-तरीकों में पारंगत हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्यप्रद खिचड़ी की महत्ता से अपरिचित हैं।”

चुनाव अभियान के दौरान जनमत अपने पक्ष में करने की विपक्ष की सीधी रणनीति हर कांग्रेसी ईट का जवाब पत्थर से देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री को लगातार लक्ष्य बनाये रखने की रही। हथियार कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा और तोप दलाली रहा, तो कभी कमरतोड़ महंगाई और प्रशासनिक अंक्षमता। सोने पर सुहागा भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों का गठबंधन रहा। अधिसंख्य विपक्षी नेता जनता को यह समझाने में सफल रहे कि वर्तमान महंगाई की जड़ कांग्रेसी चंदा वसूली और दलाली थी। उदाहरण के लिए चीनी, चाय आदि रोजमर्रा की जिन्सों की अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि को प्रस्तुत किया गया। जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यदि देश की खोई इज्जत और धन वापस लाने की बात बारम्बार दोहराई तो पार्टी महासचिव अजीत सिंह कृषक बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में यह सिद्ध करने में जुटे रहे कि कृषि प्रधान देश के ‘विदेशी’ प्रधानमंत्री जमीन की असलियत से भी नावाकिफ हैं। इस संदर्भ में चुनाव सभाओं का एक चटपटा चुटकुला यह रहा कि राजीव गांधी राजस्थान के एक मतदाता के मिर्च के खेत में गये, तो पूछा कि महंगी हरी मिर्च होती है या लाल और यह बताये जाने पर कि लाल मिर्च महंगी है, बोले, “मैं दिल्ली जाकर आदेश दूंगा कि अगली फसल के लिए लाल मिर्च के बीज भेजे जायें।”

गौरतलब है कि यदि विपक्ष कांग्रेस द्वारा उठाये मुद्दों के ताबड़तोड़ जवाब के लिए तत्पर था, तो कांग्रेस विपक्षी आरोपों से मुंह छिपाने, उन्हें अन्य मुद्दों के सहारे पृष्ठभूमि में डालने को आतुर। नतीजतन भ्रष्टाचार, दलाली, बोफोर्स और महंगाई के मुद्दों को अछूता रख कांग्रेस निरंतर अखंडता, साम्प्रदायिकता स्थिरता, एकता के मुद्दों को ही उछालती रही। विपक्ष प्रहारों ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व को इतनी अधिक रक्षात्मक मुद्रा अपनाने को विवश किया था कि उसके चलते वह अपनी तथाकथित उपलब्धियां गिनाना भी अधिकांशतः भूलता रहा। जवाब का प्रयास यदाकदा हुआ भी, तो मूल मुद्दे से हटकर। तोप दलाली की बात करने का साहस जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री डीएच अंसारी ने मुरादाबाद की एक जनसभा में जुटाया भी तो यह कहकर कि जिस परिवार ने अपना भवन (आनंद भवन) तक देश और पार्टी के लिए दान कर दिया हो, उसे ६४ करोड़ की दलाली खाने-कमाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार बरेली में प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा करती जनता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के संयुक्त सचिव डीपी राय ने बोफोर्स तोपों की चर्चा तो चलायी, किंतु बात दलाली की न कर तोप की गुणवत्ता की की। वह भी इस दलील के साथ कि “विपक्ष कहता है कि तोप नकली है। नकली है या असली। इसके फैसले के लिए मैं कहता हूं कि सभी विपक्षी नेता राजस्थान के मरुस्थल में तोप से ३० किमी की दूरी पर खड़े हो जायें। हम तोप दागेंगे। असली हुई, तो सब उड़ जायेंगे।” महंगाई का मुद्दा राम-राम कर एक महासचिव ने उठाया भी, तो यह कह कर कि ‘महंगाई का हल्ला बोलने वाले पड़ोसी देशों—पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में कीमतों का जायजा क्यों नहीं लेते।’ लाजिमी था कि ऐसी दलील पर जनता हूट करती। और यही हुआ।

यदि इंसान का खून सस्ता रहा, तो चुनाव बहुत महंगा। जीतने की होड़ में तिजोरियों के मुंह खोल दिये गये। धन्ना सेठों ने थैलियां खोलीं-प्रत्याशियों को अपनी जेब में रखने के लिए, तो प्रत्याशियों ने वोट खरीदने के लिए। इस खरीद-फरोख्त में पक्ष या विपक्ष किसी को भी अस्पृश्य नहीं समझा गया।

सांप्रदायिकता का मुद्दा : सांप्रदायिकता को प्रमुख मुद्दा बना विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का महीनों पुराना कांग्रेसी हथियार अंततः उन्हीं

पर वज्रपात कर गया। कारण प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में चुनाव-अभियान शुरू करने और रामराज्य लाने की बात करने तथा सरकार द्वारा शिलान्यास की अनुमति दे जो हिंदू समर्थन जुटाने का प्रयास हुआ, उससे हिंदू कितने साथ आये, यह विवाद का विषय रहा। किंतु मुसलमान बिफर गये यह पूर्णतया स्पष्ट रहा। जब होश आया तो पूरे जोशोखरोश से उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश शुरू हो गयी। अन्य नेताओं के अतिरिक्त महासचिव गुलाम नबी आजाद की सेवाएं विशेष रूप से ली गयीं। अंतिम सप्ताह में धुआंधार दौरों और जनसभाओं के दौरान आजाद यही समझाते रहे कि अल्पसंख्यकों का वर्तमान और भविष्य दोनों मात्र कांग्रेस के हाथों ही सुरक्षित है। कांग्रेसी नेकनीयती के सबूत के तौर पर वे अतीत के उन तीन विशिष्ट निर्णयों—शाहबानो और मुस्लिम महिला विधेयक, सलमान रुश्दी की पुस्तक पर प्रतिबंध और कलकत्ता हाईकोर्ट में अटार्नी जनरल की कोशिशों से कुरान शरीफ पर हटाये प्रतिबंध का हवाला देते रहे।

> **विश्व के इस विशालतम और निर्धनतम लोकतंत्र में प्रसार-प्रचार अभियान का चुनावी अंकगणित कुछ ऐसा गड़बड़ाया है कि वह दिनोदिन शरीफ और गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यदि समय रहते इस संक्रामक रोग का उपचार न हुआ, तो न लोकतंत्र की यह स्वस्थ काया बचेगी न उसकी आत्मा।**

मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के प्रयास विपक्ष विशेषकर जनता दल ने भी कुछ कम नहीं किये। इसी कारण भाजपा से पहले सीटों के तालमेल पर रस्साकशी हुई। आधेअधूरे तालमेल के बावजूद भाजपा के साथ एक मंच पर न जाने का निर्णय और इसी प्रश्न पर जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह की मथुरा में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील न करने की मुद्रा भाजपा की अवमानना की इच्छा से कम प्रेरित थी, मुसलमानों को आश्वस्त करनें की अधिक थी। जामा मस्जिद के शाही इमाम को अपनी ओर करने के महीनों पुराने विपक्षी प्रयास तब रंग लाये, जब चुनाव पूर्व उन्होंने जनता दल को समर्थन देने का फतवा जारी कर दिया।

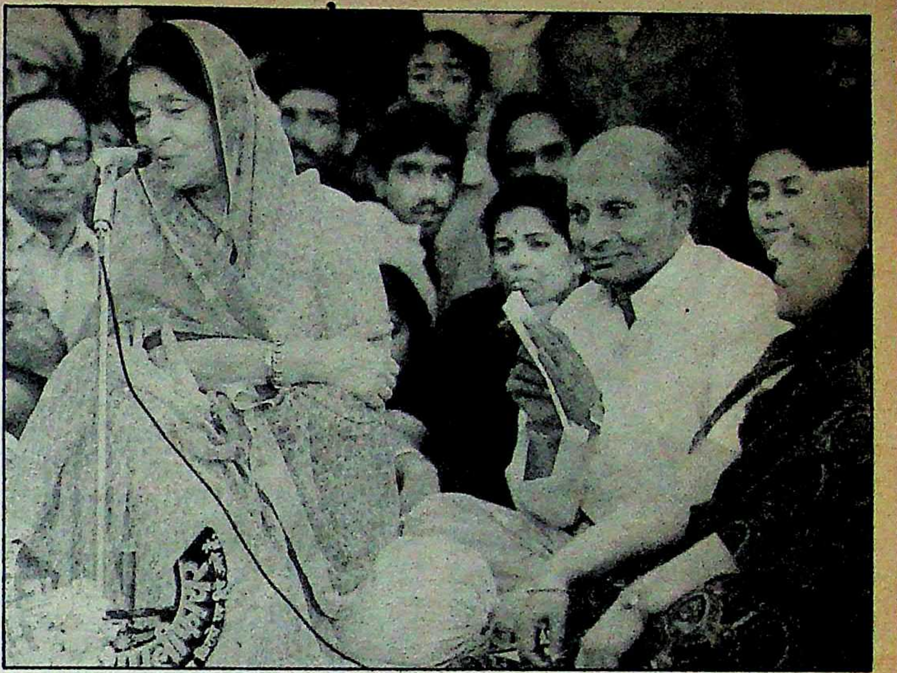

पुत्र को मात : एक चुनाव सभा में राजमाता गायत्री देवी

छाया : प्रताप सिंह

अभियान का दिलचस्प पहलू यह रहा कि कांग्रेस उत्तर में रक्षात्मक रही, किंतु दक्षिण में उसका रुख आक्रामक रहा। उत्तर में अपने ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार, भाई, भतीजावाद, प्रशासनिक निकम्मेपन आदि के विपक्षी आरोपों को कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में रामाराव की तेलुगूदेशम सरकार, तमिलनाडु में कुछ महीनों पुरानी करुणानिधि की द्रमुक सरकार, कर्नाटक में विफल जनता दल और केरल में वामपंथी मोर्चा सरकार पर मियां की जूतों मियां के सर की तर्ज पर इस्तेमाल किया।

विमान सुविधा : प्रचार अभियान के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को विमान यात्राओं की सुविधा के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी और बंबई से कलकत्ता तक फेरे लगाने की सुविधा रही। इसके विपरीत जनता दल अध्यक्ष को हवाई यात्रा की सुविधा न होने और इंडियन एयरलाइंस के अपने कटु अनुभव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना प्रचार कार्य सीमित रखना पड़ा। यह असुविधा अंततः राजा मांडा के लिए वरदान साबित हुई। कारण सड़क से यात्रा करने से उनका जनसंपर्क अपेक्षाकृत सघन और प्रभावी रहा। निर्धारित जनसभाओं के अतिरिक्त वीपी सिंह को सड़क यात्रा की धूल और गर्द के बीच अनियोजित लघु जनसभाओं द्वारा जनता के बीच जाने और पहचान बनाने के अनगिनत मौके मिले। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने माहौल भी बनाया और जनमत भी अपने पक्ष में किया। सड़क नापने वाले वे अकेले नेता नहीं थे। पूरे उत्तर भारत में विपक्ष, विशेषकर जनता दल और भाजपा के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा की गयी यात्राओं से उड़ने वाली धूल कांग्रेस को ढांपने में पर्याप्त रही।

यशवंत सिन्हा के अनुसार कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष को साधनों की कमी अवश्य रही, किंतु क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं की भरमार ने इस कमी को बहुत प्रभावी ढंग से पूरा किया। वीपी सिंह के अनुसार, "कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी के साथ-साथ उनमें निष्ठा की कमी भी थी। अंतिम समय में जुड़ने वाले लोग अधिकांशतया बंद होते कांग्रेस से 'वाइंडिंग अप चार्जेज' वसूलने की नीयत से आये थे।" ऐसे लोगों का प्रचार कार्य निष्प्रभावी होना ही था।

इस चुनाव में शासक दल के विरुद्ध माहौल पैदा करने का जितना योगदान विपक्षी दलों का रहा, उससे कहीं अधिक मीडिया का रहा, ऐसा विपक्षी नेताओं का मानना है। दूरदर्शन को सरकार ने पिछले वर्षों में यद्यपि इतना पाला-पोसा, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा इस मीडिया के शासक दल द्वारा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देने से उनके हाथ कट गये। समाचार पत्रों-पत्रिकाओं के तो पहले से ही विरोधी तेवर उजागर थे, जिसका पूरा लाभ विपक्ष के खाते में गया।

विश्व के इस विशालतम और निर्धनतम लोकतंत्र में प्रसार-प्रचार अभियान का चुनावी अंकगणित कुछ ऐसा गड़बड़ाया है कि वह दिनोदिन शरीफ और गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यदि समय रहते इस संक्रामक रोग का उपचार न हुआ, तो न लोकतंत्र की यह स्वस्थ काया बचेगी न उसकी आत्मा।

—रंजना कक्कड़
बिशन कुमार के साथ

चुनाव विश्लेषण

मतदाताओं की समझ

चुनाव परिणाम अप्रत्याशित भले ही लगें, लेकिन बारीकी से देखा जाये, तो मतदाताओं के रुझान की एक सुनिश्चित दिशा रही है। उत्तर-दक्षिण में मतदाताओं का परस्पर विरोधी दोटूक फैसला इसी का परिचायक है। चुनाव से पहले जिन मुद्दों को निर्णायक समझा गया था, क्या वे निर्णायक सिद्ध हुए? भिन्न-भिन्न स्थानों पर मतदाता के निर्णय को किन-किन परिस्थितियों ने प्रभावित किया और क्यों?

व्यवस्था विरुद्ध : युवा मतदाता छाया : राजेंद्र कुमार

नौवीं लोकसभा का चुनाव यदि सर्वाधिक वीभत्स, हिंसक और खर्चीला रहा, तो परिणाम उतने ही ऐतिहासिक। लगभग ५० करोड़ भारतीय मतदाताओं ने चुनावी हार-जीत में अपनी सर्वोच्चता, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, परिपक्वता और जागरूकता का परिचय दिया है। उत्तर में सत्तापक्ष कांग्रेस और दक्षिण में सत्तारूढ़ गैरकांग्रेसी दलों के खिलाफ मूक किंतु दोटूक फैसला सुनाकर उन्होंने सिद्ध किया है कि न तो उन्हें रिझा-पटा प्रभावित किया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। न मूर्ख बनाया जा सकता है और न ही उनकी उपेक्षा की जा सकती है। चुनाव नतीजों द्वारा उन्होंने यह भी जता दिया कि यदि वे ताज पहनाते हैं, तो ताज की लाज न रखने वालों का तख्तोताज पलक झपकते पलट सकने की हिम्मत-हैसियत भी रखते हैं। इसीलिए इस बार का मतदान परिवर्तन का भी सूचक रहा, प्रतिरोध का भी।

अभूतपूर्व चुनाव : चुनाव अभूतपूर्व अन्य मायनों में भी रहा। पक्ष-विपक्ष में परिणाम संबंधी विपरीत दावों का होना लाजिमी था। ज्ञात रहे कि विपक्ष यदि कांग्रेस को सौ-सवा सौ सीटें देने की बात कर रहा था, तो कांग्रेस ताल ठोंक कर तीन-साढ़े तीन सौ सीटों पर विजयश्री का दम अंतिम क्षणों तक भरती रही। तथाकथित निष्पक्ष पर्यवेक्षक भी आने वाले उन परिणामों की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, जिनके तहत कांग्रेस के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए मतदाताओं ने—विशेषकर उत्तर भारत के—मात्र १९३ सीटें देकर उसे केंद्र में सत्ताच्युत किया। किंतु विपक्ष के भी किसी एक दल को पूर्ण समर्थन नहीं दिया। यहां तक कि पांच पार्टियों—जनता दल, तेलुगूदेशम, द्रमुक, अगप व समाजवादी कांग्रेस—से बने राष्ट्रीय मोर्चे को स्पष्ट बहुमत मिलना तो दूर जनता दल (जिसे १४१ सीटें हासिल हुई हैं) के अतिरिक्त उसके तीन अन्य घटकों को मात्र ३ सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम इतने विचित्र रहे कि दक्षिण भारत में संपूर्ण विपक्ष को—जिसमें वाम व दक्षिण दोनों शामिल हैं—मात्र ७ सीटें प्राप्त हुई हैं।

विभाजित परिणाम : इस प्रकार का उत्तर-दक्षिण का 'विभाजित चुनाव परिणाम' पहली बार देखने को नहीं मिला। १९७७ में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में भी इसी प्रकार का विषम राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आया था। फर्क यह है कि उस समय दक्षिण से तो विपक्ष को कुल ६ सीटें मिली थीं, किंतु उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो जाने के कारण उसे कुल १५४ सीटें ही मिल पायी थीं। नतीजतन तत्कालीन जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनायी थी। वर्तमान चुनाव परिणाम ऐसे रहे हैं कि विपक्ष को दक्षिण में तो मात्र एक सीट का लाभ हुआ है, किंतु उत्तर भारत में राजस्थान को छोड़कर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया न होने के कारण उसे न केवल १९३ सीटें मिलीं, बल्कि सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी का श्रेय भी प्राप्त हुआ। दूसरी ओर बहुमत प्राप्त न होने के कारण राष्ट्रीय मोर्चा अल्पमत सरकार बनाने के लिए दो विपरीत ध्रुवों पर बैठे भाजपा व वामपंथी मोर्चे की सहायता लेकर आगे बढ़ने का दुष्कर काम सरंजाम देने को विवश है।

उत्तर-दक्षिण के चुनाव परिणामों में इतना अधिक अंतर और स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण विपक्षी खेमे में विजय हासिल करने का जो हर्षोल्लास होना चाहिए, उसमें चिंता का ग्रहण लगा हुआ है। दूसरी ओर दशकों से सत्ता-सुख भोगने वाले कांग्रेसी खेमे में पराजय के बाद हताशा, निराशा का जो घटाटोप होना चाहिए था, वहां आशा की किरण उजागर है। प्रश्न यह है कि ऐसे अस्पष्ट व अंतर्विरोधी चुनाव नतीजे क्यों आये और अंततः ये क्या रंग लायेंगे?

विभाजित मानसिकता : दक्षिण के प्रख्यात पत्रकार, पर्यवेक्षक चो रामास्वामी के अनुसार, "यह उत्तर-दक्षिण की विभाजित मानसिकता का ही परिचायक है। चुनावी परीक्षा में गणित कांग्रेस के विरुद्ध गया है। इतिहास चाहे कांग्रेस के लिए सहायक सिद्ध न हुआ हो, किंतु भूगोल निश्चय ही मददगार हुआ है। उल्लेखनीय है कि ५४५ सदस्यों वाली लोकसभा में दक्षिण के प्रमुख चार राज्यों की कुल सीटें मात्र १२९ हैं। इसलिए निर्णायक भूमिका उत्तर भारत की हो जाती है, जहां कांग्रेस मात खा गयी है।" प्रसिद्ध विचारक मधु लिमये उत्तर दक्षिण के विभाजन की इस दलील से सहमत नहीं। 'माया' से बातचीत में उन्होंने कहा, "जिसने भी सत्ता का दुरुपयोग किया, उसे ही मतदाताओं ने भरपूर सबक सिखाया। दक्षिण में विपक्ष उत्तरदायी था, तो शेष भारत में कांग्रेस। जनता ने हिसाब भी इसी अनुपात में चुकता किया।"

कांग्रेस के उत्तर में लगभग सफाये से कहीं अधिक चौंकाने वाले नतीजे आंध्र प्रदेश के रहे। यहां अभिनेता से नेता बने एनटी रामाराव न केवल आंध्र प्रदेश में नायक थे, बल्कि राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। उनके

आत्मविश्वास का आलम यह था कि लोकसभा चुनाव के साथ उन्होंने राज्य के विधानसभा चुनाव कराने की भी घोषणा कर दी थी। यही निर्णय उनके लिए अंततः बेहद महंगा साबित हुआ। रामाराव की इस चुनाव घोषणा के शीघ्र बाद 'माया' से बातचीत में जनता दल के पूर्व सांसद जयपाल रेड्डी ने आशंका प्रकट करते हुए 'माया' को बताया, "अब मुझे अपनी सीट (लोकसभा) जीतने के लिए उस क्षेत्र के सात विधायकों का बोझ भी ढोना पड़ेगा।"

चुनाव में एनटीआर विरोधी ऐसी आंधी चली कि उसमें बहने वाले अनेक जाने-माने सांसदों में रेड्डी भी रहे। परिणामस्वरूप '८४ की राजीव गांधी की आंधी में ४२ में से ३० सीटें जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी धड़ा बनने वाली तेलुगूदेशंम को इस बार मात्र २ सीटें हासिल हुईं। विधानसभा हाथ से निकल गयी सो अलग। एक समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे रामाराव की फजीहत की हद यह रही कि वे विधानसभा की उस सीट से एक नौजवान के हाथों स्वयं पराजित हो गये जिसे जयपाल रेड्डी ७१, '७८ और ८३ में जीतते चले आये थे। इस आश्चर्यजनक हार का मूल कारण स्थानीय मुद्दे सर्वोपरि हो गये और राष्ट्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गये। तेलुगूदेशम को शून्य से शिखर पर ले जाने वाले यदि रामाराव थे, तो उसकी वर्तमान शोचनीय स्थिति के लिए भी वे स्वयं जिम्मेदार हैं, ऐसा अनेक पर्यवेक्षकों का मानना है। कारण न केवल वे स्वयं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, निरंकुशता, कुव्यवस्था के आरोपों के घेरे में थे बल्कि उनके नाटकीय लटकों-झटकों से जनता आजिज आ चुकी थी। रही-सही कसर प्रत्याशियों के चयन के उनके नादिरशाही रवैये ने पूरी कर दी। इसके अतिरिक्त कुछ समय पूर्व की उनकी रातोरात की संपूर्ण मंत्रिमंडल बदलने की कार्रवाई से एक ओर जहां उनके अपने लगभग तीन दर्जन पूर्व मंत्री खार खाये बैठे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक मोहन रंगा की नृशंस हत्या से संपूर्ण कप्पू समुदाय बिफर चुका था।

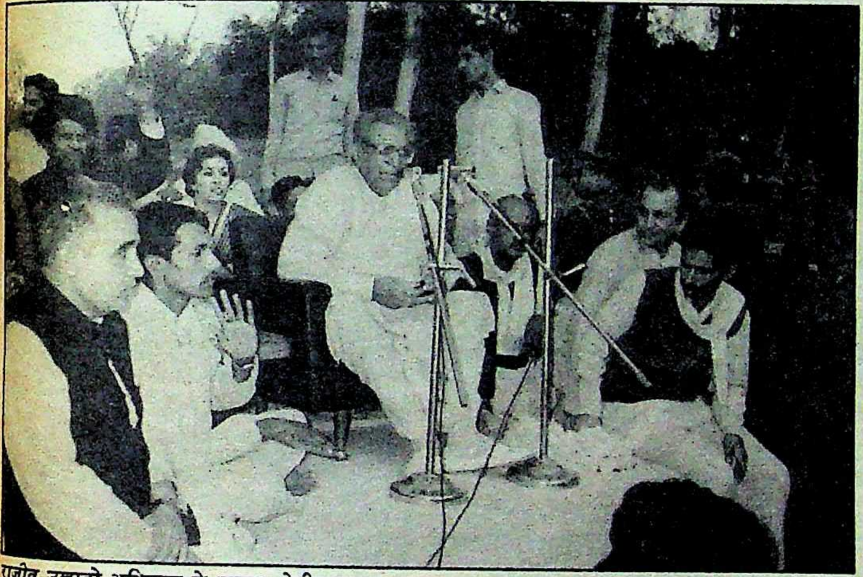

राजीव उखाड़ो अभियान के जनक: देवीलाल

छाया: मानसरोवर शर्मा

विजयका फल: वीपी अपने प्रिय समर्थकों के साथ

छाया: मनमोहन शर्मा

खलनायक कौन ? : कर्नाटक के नाटक की खलनायक स्वयं वर्षों सत्तारूढ़ रही जनता पार्टी (बाद में जनता दल) थी। उल्लेखनीय है कि आदर्श के रूप में पेश की जाने वाली कर्नाटक की जनता सरकार पर पहला ग्रहण तब लगा, जब अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाये जाने के मुद्दे पर चंद्रशेखर व राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े में ठन गयी। इसी प्रकरण में बहुचर्चित टेलीफोन टेप कांड मुद्दे पर हेगड़े को गद्दी छोड़नी पड़ी। दूसरी क्षति तब पहुंची, जब जनता दल बना और देवगौड़ा ने पार्टी विभाजित कर पूर्व जनता पार्टी बनाये रखने का फैसला किया। जनता दल व जनता पार्टी के बीच और जनता दल के अपने घटकों के अंतर्कलह से बोम्मई सरकार गिर गयी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इन सबके बीच मूल्य-आधारित राजनीति की वकालत करनेवाले पूर्व मुख्यमंत्री हेगड़े के कथित भ्रष्टाचारों के भंडाफोड़ ने रही-सही कसर पूरी कर दी। जनता दल के प्रति जनता के मोहभंग का पहला संकेत तब मिला, जब बोम्मई सरकार गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू होने के विरोध में जनांदोलन चलाने का प्रयास विफल हो गया। वर्तमान चुनाव पूर्व विपक्ष ने अपेक्षा की थी कि चूंकि बोम्मई सरकार केंद्र के हथकंडों से गिराई गयी है, इसलिए उसे सहानुभूति वोट प्राप्त होंगे। किंतु मतदाताओं ने सहानुभूति की जगह सबक दिया—वह भी पक्षपातरहित होकर। हेगड़े को तो सत्ता से अलग रखा ही, पार्टी विभाजित करने वाले देवगौड़ा को भी नहीं बख्शा और उन्हें एक नहीं दो-दो जगह हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजतन दुबारा सत्तारूढ़ होने का मंसूबा पालनेवाली जनता दल को विधान सभा की २२४ सीटों में से २४ सीट और लोकसभा की २८ में से मात्र एक सीट से ही संतोष करना पड़ा।

एक मायने में तमिलनाडु नतीजों को आश्चर्यजनक नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में हुए विधानसभा चुनावों में द्रमुक, वोटों के विभाजन के कारण, मात्र ३३ प्रतिशत वोट पाकर सत्तारूढ़ हो गया था। इस बार उत्तर भारत में एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार होने से विपक्ष लाभान्वित हुआ है, तो दक्षिण और खासकर-तमिलनाडु में कांग्रेस—अन्नाद्रमुक गठजोड़ के कारण द्रमुक का खाता भी नहीं खुला। बावजूद इसके कि विधानसभा चुनाव की तुलना में

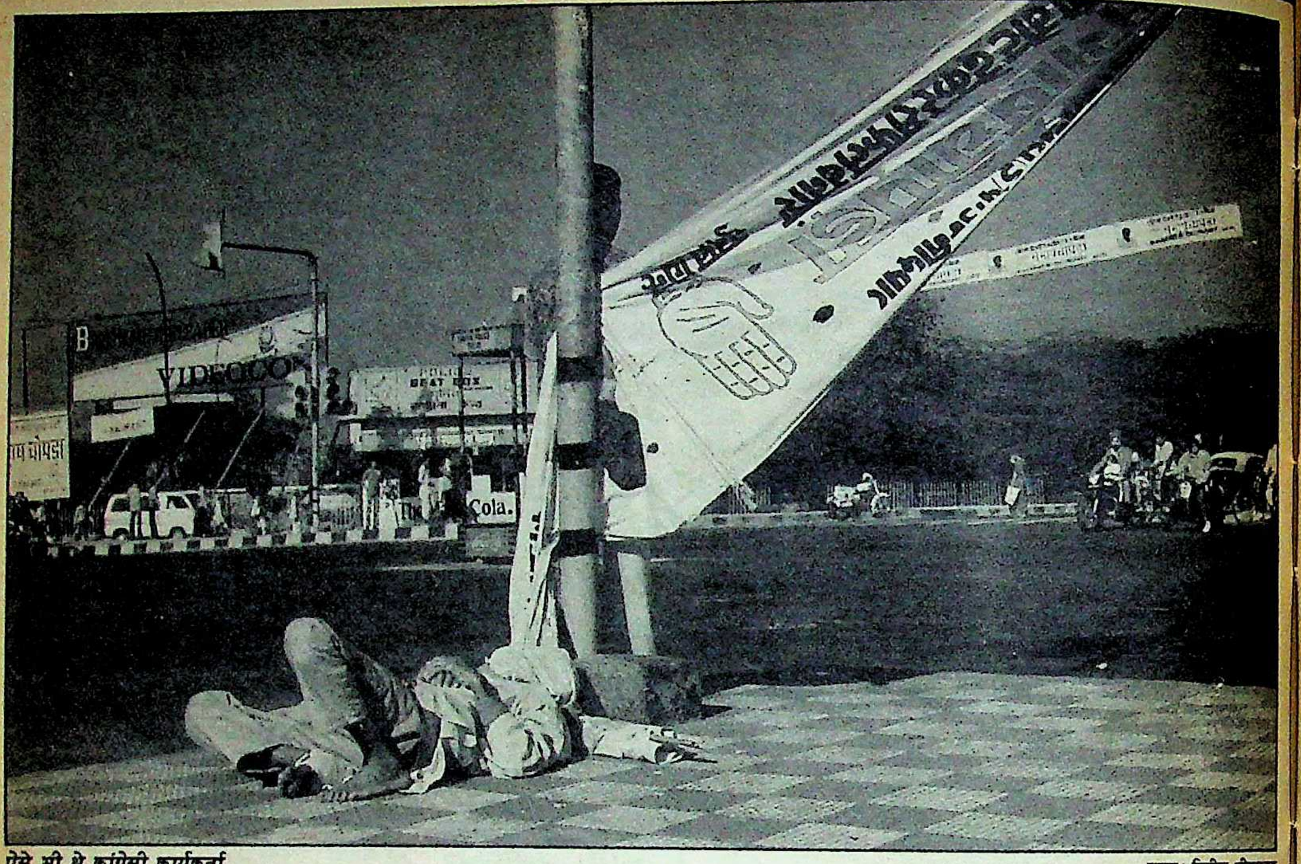

ऐसे भी थे कांग्रेसी कार्यकर्ता

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

उसके (द्रमुक) मतों में थोड़ी वृद्धि हुई। कांग्रेस की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ यह तो पता नहीं, किंतु एमजी रामचंद्रन की वारिस के रूप में जयललिता की लोकप्रियता ने चुनाव नतीजों को निश्चय ही प्रभावित किया। एक पर्यवेक्षक बोले, "द्रमुक के सत्तारूढ़ होने के बाद विधानसभा में जयललिता के साथ हुए दुर्व्यवहार ने 'द्रौपदी चीर हरण' जैसी सहानुभूति लहर उनके पक्ष में कर दी थी।"

दूसरी ओर विपक्षी एकजुटता की हौसला अफ़जाई करने वाले देवीलाल के अपने किले में सेंध लग गयी। ढाई वर्ष पूर्व जिस देवीलाल ने ९० सीटों वाली विधानसभा में मात्र ५ सीटें देने का मौका दिया था और जहां के जनता दल राज्य अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला १० की दसों लोकसभा सीटें जीतने अन्यथा राजनीति से संन्यास लेने का दम भर रहे थे वहां ६-४ का बंटवारा हुआ। पराजित लोगों में—सुषमा स्वराज, सूरजभान और जनता दल के धर्मवीर शामिल हैं। वह भी बकौल प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष एस एस कुंडू, 'बंदूकों के साये तले।' बंदूकों-गुंडों का सहारा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों बंसीलाल व भजनलाल ने भी लिया। नतीजतन उनकी अपनी सीटें बची रहीं। उत्तर में कांग्रेस विरोधी आंधी के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस को मिली सफलता के पीछे कारण देवीलाल का परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था रही है। मधुलिमये के अनुसार हालत तो बदतर होती यदि देवीलाल वीपी सिंह के कंधे पर सवार न होते।

बदलाव की इच्छा : केरल ने कांग्रेस को जो अभूतपूर्व जनसमर्थन प्रदान किया उसे पर्यवेक्षक जनता में बदलाव की इच्छा और सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार के प्रति आक्रोश-असंतोष मानते हैं। गौरतलब है कि केरल राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक ध्रुवीकृत राज्य है और यहां हार-जीत बहुत कम मतों से होती रही है। ऐसी स्थिति में वहां भाजपा ने त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो मोर्चा खोला उससे भी कांग्रेस को लगभग आधा दर्जन सीटों का लाभ हुआ। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण के बेटे की कालीकट से जीत में सीधे-सीधे भाजपा का हाथ देखा गया। कांग्रेस के केरल में खेले गये ईसाई कार्ड ने भी वाम मोर्चा को सांसत में डाला।

परिवर्तन की इच्छा का अपवाद लगभग एक दशक से वाम मोर्चा शासित पश्चिम बंगाल रहा। यद्यपि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी व पूर्व सांसद ममता बनर्जी इसे होशियारी से की गयी चुनावी धांधली करार देते हैं। किंतु अधिकांश पर्यवेक्षक वाममोर्चा सरकार व खासकर ज्योति बसु की साख व राज्य कांग्रेस में फूट को मुख्य कारण बताते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार दास मुंशी की हार में उनकी ही पार्टी के उन दिग्गजों का हाथ रहा जो उन्हें हर हाल नाकाम होते देखना चाहते थे।

कांग्रेस के बीच गुटबंदी और एक दूसरे की टांगखिचाई का यही रोग उत्तर भारत में मारक सिद्ध हुआ। हिंदीभाषी क्षेत्र का एक राज्य भी इस रोग से मुक्त नहीं था। कांग्रेस के लिए रेगिस्तान बने राजस्थान (जहां एक भी सीट नहीं मिली) में तो इस धड़ेबंदी और कुशासन के प्रति व्यापक जनअसंतोष इस चरम पर जा पहुंचा कि स्वयं माथुर सरकार के ५ मंत्री जिनमें प्रदेशाध्यक्ष अशोक गहलोत तथा चार दिग्गज केंद्रीय मंत्री—बूटा सिंह, लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़, रामनिवास मिर्धा, राजेश पायलट खेत रहे। गुटबंदी का आधार पुरानी रंजिश और भावी प्रतिद्वंद्विता के अतिरिक्त जातीय समीकरण भी रहे। जानकार सूत्रों के अनुसार दौसा की सीट पर बुजुर्ग कांग्रेसी नवल किशोर शर्मा के विरुद्ध खड़े गूजर प्रत्याशी के समर्थक कोई अन्य नहीं गूजरों के नये झंडाबरदार राजेश पायलट थे। यह दीगर बात है कि भरतपुर में उनकी अपनी जड़ों में मट्ठा डालने का काम मथुरा में बैठे दूसरे केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह कर रहे थे।

गुटबंदी का खमियाजा : गुटबंदी का सबसे

ज्यादा खमियाजा कांग्रेस को मप्र, उप्र, बिहार व महाराष्ट्र में उठाना पड़ा। मप्र हमेशा से ही दो-तीन धड़ों में बंटा रहा है। इसी के चलते मोतीलाल वोरा महीनों पहले मुख्यमंत्री बनने के बावजूद पैर जमाने और टिकाऊ और कारगर शासन प्रदान करने में विफल रहे हैं। उप्र में तो हालत इससे भी बदतर है। पहले तो मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की वफादरी पर ही आलाकमान को संदेह था। दूसरे तिवारी गुट और उप्र के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद गुट के बीच जो ३६ का रिश्ता है उसने विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य भी प्रतिद्वंद्विता बरकरार रखी। यह मुरादाबाद में तिवारी गुट की लोकसभा प्रत्याशी इंद्र मोहिनी और विधानसभा सीट के प्रत्याशी पूर्व सांसद हाफिज इब्राहिम के मध्य छिड़े शीत युद्ध से उजागर था जिसके चलते १७ नवंबर तक दोनों की कोई संयुक्त सभा नहीं हुई। और तो और इंद्र मोहिनी के समर्थक वोट मांगते नारे लगा रहे थे 'ऊपर दो मैया को नीचे दो भैया को'। और भैया का अर्थ कांग्रेस से नहीं भाजपा उम्मीदवार से था। इससे आग बबूला हुए कांग्रेस महासचिव आजाद को सार्वजनिक रूप से समस्त कार्यकर्ताओं-नेताओं को यह कहकर फटकारना पड़ा था कि वोट व्यक्ति के लिए नहीं पार्टी के लिए है। रही-सही कसर तिवारी द्वारा सुझाये उन विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी जिसकी रणनीति विपक्ष को तितर-बितर करने की थी। किन्तु छितर-बितर कांग्रेस गयी।

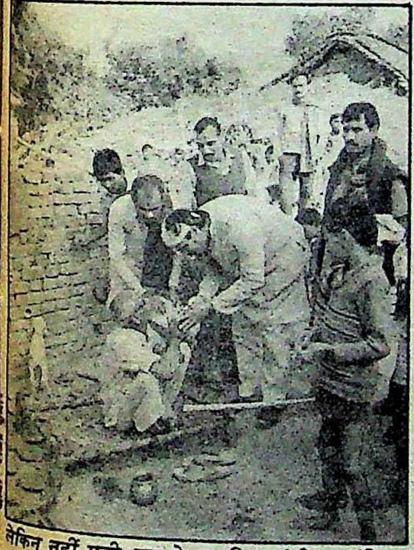

लेकिन नहीं सुनी: उप्र के पराजित मंत्री जगदंबिका

बिहार में हार की मार तो इतनी गहरी रही कि ५४ में से कुल चार सीटें बमुश्किल निकलीं। गुटबंदी ने इसमें खुलकर खेल दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद को भागलपुर और पूर्व पार्टी प्रदेशाध्यक्ष तारिक अनवर को कटिहार में हराने का श्रेय स्वयं अनेक कांग्रेसी, वर्तमान मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और निर्वतमान मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा को दे रहे हैं। गुटबंदी से ग्रस्त कांग्रेस के लिए भागलपुर दंगे ताबूत में अंतिम कील साबित हुए।

कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ महाराष्ट्र में जो विपक्षी सेंध लगी है उसने मुख्यमंत्री पवार के 'पावर' को कम कर दिया है। वैसे तो कांग्रेस को राज्य की ४८ सीटों में से २८ सीटें मिली हैं, किंतु यह अनुपात १९७७ की तुलना में भी कम है। कांग्रेस महासचिव विट्ठल नरहरि गाडगिल ने 'माया' को बताया, "चिंता का कारण विदर्भ क्षेत्र की हुई क्षति है। १९७८ के कांग्रेस विरोधी माहौल के बावजूद इस क्षेत्र में जनाधार इतना सुदृढ़ था कि हमारे ५८ विधायक चुने गये थे।" महाराष्ट्र में जो थोड़ी बहुत बचत हुई वह भाजपा-शिवसेना गठजोड़ व जनता दल के अलग-अलग मोर्चे खुलने के बहुकोणीय संघर्ष के कारण। गुजरात, जहां भाजपा-जनता दल में पूर्ण तालमेल था और कांग्रेस का अंतर्कलह बरकरार था, वहां उसे १९८४ की २६ में से २५ सीटों की तुलना में मात्र ३ सीटें मिली हैं।

नाटकीय राजनीति का विरोध: एनटीआर

गुटबंदी के अलावा कांग्रेस विरोधी हवा बनाने में भ्रष्टाचार और महंगाई ने अहम भूमिका निभायी। बोफोर्स स्वयं कितना घातक सिद्ध हुआ इस विषय में पक्ष-विपक्ष में मतभेद है। महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद गाडगिल का दावा है कि इसका सीमित और शहरी क्षेत्रों में प्रभाव रहा। इसके विपरीत ग्रामीण इलाके प्रधान राजापुर (महाराष्ट्र) से पांचवीं बार निर्वाचित जनता दल के सांसद मधु दंडवते के अनुसार बोफोर्स घोटाले के बारे में जानकारी और प्रभाव छोटे से छोटे गांवों में था।

चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी क्षेत्र के निकट के एक विधानसभा प्रत्याशी के साथ 'माया' टीम के दौरे के दौरान एक जगह प्रत्याशी को जीप तक छोड़ने आये स्थानीय ठाकुर ने यकायक पूछा, "भइया सच-सच बतावा का राजीव दलाली खाये हैं?"

"होई सकत है खायें हों। पर हम नहीं खावा" का अप्रत्याशित उत्तर सुन 'माया' टीम अचरज में पड़ गयी। जीप स्टार्ट होने के बाद 'माया' ने जब पूछा कि ऐसा उत्तर उन्होंने क्यों दिया तो जवाब मिला, "हम हियां और का कहत? हियां वोट मांगन आये रहैं। बहस औ मारपीट करन नाहीं।"

बोफोर्स का प्रभाव : बोफोर्स ने मतदान को कितना प्रभावित किया यह बहस का मुद्दा हो सकता है, किंतु इसने कांग्रेसी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को पस्त हिम्मत किया इसमें दो राय नहीं। बोफोर्स और भ्रष्टाचार के मुद्दे को विपक्ष ने जहां लगातार अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया, वहीं कांग्रेस इससे या तो आंखें चुराती रही या आधे-अधूरे जवाबों से लगभग इकरार करती रही।

इसी प्रकार का शुतुरमुर्गी रवैया उसने महंगाई के मुद्दे पर भी अपनाया। विपक्ष आम जिंसों—चाय, चीनी, बीड़ी आदि की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की याद के गोले निरंतर अपनी हर जनसभा में दागता रहा, तो कांग्रेस इस मुद्दे से पीठ दिखाती रही। शुरू से ही प्रतिरक्षात्मक मुद्रा अपनाने को बाध्य कांग्रेस में बदहवासी कुछ ऐसी फैली कि वह अपनी उपलब्धियों तक को गिनाना भूल गयी। यहां तक कि विपक्ष द्वारा पराजित जिस पंचायत राज विधेयक को लेकर उसने चुनाव की घोषणा की थी उसे भी वह भुना न सकी। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए मैदान मारना आसान रहा।

कांग्रेसियों के अनुसार वे चुनाव उसी दिन हार गये थे जब टिकट वितरण हुआ। इसका खुलासा करते हुए स्व० केडी मालवीय की पुत्री आशा मालवीय ने, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय थीं, 'माया' को बताया, "अधिकांश पूर्व सांसदों ने पिछले पांच सालों में अपने क्षेत्र का विकास कार्यक्रम चलाना तो दरकिनार, वहां अपना मुंह पांच बार भी नहीं दिखाया था। ऐसे लोगों के दुबारा प्रत्याशी बनने पर जनता द्वारा उनका पत्ता साफ करना आश्चर्यजनक नहीं।" पुरानों के अतिरिक्त बिना समुचित जांच-परख के गलत लोगों को प्रत्याशी बनाना भी भारी पड़ा। इसका ज्वलन्त उदाहरण 'माया' को अमरोहा चुनाव प्रचार के लिए गये प्रभावी महासचिव गुलाम नबी आजाद की एक जनसभा में देखने को मिला। आजाद जिस समय मंच से कांग्रेसी प्रत्याशी का समर्थन जुटाने में जुटे थे, तो उनके बिल्लाधारी कार्यकर्ता मंच के नीचे 'माया' के आगे अपना दुखड़ा रोते, प्रत्याशी का कच्चा-चिट्ठा खोल यह बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने आलाकमान तक को पत्र भेजकर उनके विरुद्ध शिकायतों का पुलिंदा भेजा था। किंतु सजा देना तो दूर उन्हें टिकट से पुरस्कृत कर सभी को धर्मसंकट में डाला गया। काम करना तो दूर उनके सामने मतदान के भी दो ही विकल्प थे, या तो घर बैठे रहें अथवा वोट जनता दल के उम्मीदवार मास्टर हरगोविंद को दे दें।

पुरानों को टिकट देने अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा करने का चुनाव परिणाम पर असर गौण रहा ऐसा नवल किशोर शर्मा का मानना है। "करनाल में भाजपा मंत्री सुषमा स्वराज को हराने वाले चिरंजीलाल शर्मा के बारे

नौकरशाहों पर गाज ?

अमरीका में तो सरकार बदलने के साथ नौकरशाही के तबादले की परंपरा पुरानी है, किंतु भारत में ऐसी प्रथा नहीं। मात्र १९७७ में श्रीमती गांधी के सत्ताच्युत होने के बाद उनके चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों के सर पर गाज जरूरी गिरी थी। हाल के सत्ता-परिवर्तन के पश्चात नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल, तरक्की, तबादले, बर्खास्तगी की चर्चा राजधानी के सत्ता-गलियारों में आम है। यही कारण है कि चुनाव-नतीजों के साथ ज्यों-ज्यों विपक्ष का पलड़ा भारी होता गया, नौकरशाहों की रातों की नींद गायब होती गयी। अनेक भयभीत नौकरशाह तो अपनी जेब में इस्तीफा लिये घूमते बताये जाने लगे। राजीव गांधी के सखा-सलाहकार मणिशंकर अय्यर के चुनाव-घोषणा के ऐन दो दिन पूर्व, सेवानिवृत्त हो कांग्रेस में शामिल होने का यही मूल कारण बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि विदेशसेवा से प्रधानमंत्री कार्यालय में आनेवाले अय्यर प्रधानमंत्री के भाषण लिखने के अलावा पंचायत राज विधेयक के रचयिता भी रहे।

सत्ता और पूर्व प्रधानमंत्री के इर्दगिर्द मंडरानेवाले अन्य अनेक नौकरशाह भी अपने दिन गिनते नजर आ रहे हैं। कारण, उन्हें अहसास है कि यदि १९७७ में छोटे पैमाने पर तबादले हुए थे, तो इस बार थोक के भाव होंगे। विशेषकर इसलिए क्योंकि नौकरशाहों का जितना अधिक राजनीतिकरण राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ, उतना कदाचित पहले कभी नहीं। आलम यह था कि प्रशासनिक कार्यों से अधिक नौकरशाह राजनीतिक दांवपेंच और जोड़-तोड़ में समय लगाते दिखायी देने लगे थे। यह बात विपक्ष को ही नहीं, स्वयं सत्ता दल के नेताओं-मंत्रियों को भी खटकने लगी थी। गत अगस्त में विपक्ष के 'भारत बंद' को विफल बनाने की पूरी रणनीति—जो बाद में औंधे मुंह गिर गयी—प्रमुख सचिव बीजी देशमुख और कैबिनेट सचिव टीएन शेषन के सुपुर्द थी। राजीव शासनकाल के अंतिम चरण में बैरी बने—पत्र-पत्रिकाओं को रिझाने-पटाने की जटिल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के उस प्रेस सलाहकार जी पार्थसारथी की थी जिनके बारे में मशहूर था नियम-परंपरा तोड़कर समाचार-विचार छपवाने-दबवाने में वे अव्वल हैं। कदाचित इसीलिये वे राजीव राज्य की वापसी की न सिर्फ मनौतियां ही मना रहे थे, वरन सक्रिय भी थे। इस संबंध में मतदान के ऐन पूर्व 'माया' से बातचीत करते एक उच्चाधिकारी ने दो तथ्यों को स्वीकारा था। एक, कि नौकरशाही चुनाव-परिणामों को मनचाहा रंग देने में तीस प्रतिशत तक सक्षम है। दूसरे, राजीव की वापसी इसलिये वांछित है क्योंकि उनके शासनकाल में नौकरशाही को पहली बार खुलकर देश पर शासन करने का अवसर मिला है। चुनाव के पश्चात उनकी कारगुजारियों का खुलासा होना और उन पर गाज गिरना लाजिमी है।

साउथ ब्लाक में जोरदार चर्चा थी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ दो लोगों की विदाई सुनिश्चित है। एक कैबिनट सचिवालय के विशेष सेवा अधिकारी आरके धवन, जो चार साल के वनवास के बाद इस वर्ष के शुरू में बहाल हुए थे। दूसरे राजीव गांधी के निजी सचिव विनसेट जार्ज जो धवन की भांति सरकारी कर्मचारी नहीं। जानकार सूत्रों के अनुसार धवन और जार्ज कांग्रेस पार्टी के किसी महत्वपूर्ण काम को सरंजाम दें, तो आश्चर्य नहीं।

मणिशंकर अय्यर

आरके धवन

प्रमुख सचिव बीजी देशमुख, जिनका कार्यकाल वैसे भी पूरा हो चुका है, की जल्दी ही विदाई की संभावना है। इसी प्रकार राजीव के 'खासुलखास आदमी' कहे जानेवाले कैबिनेट सचिव टीएन शेषन नई सरकार का कोपभाजन बनेंगे, ऐसा एक विपक्षी नेता का मानना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव आर वासुदेवन के तबादले की संभावना भी बलवती है। पार्थसारथी की कारगुजारियां उन्हें शीघ्र अपने पूर्व कार्यक्षेत्र विदेश सेवा में ही नहीं, कहीं दूरदराज क्षेत्र में पटक दें, तो ताज्जुब नहीं। पार्थसारथी के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े तीन अन्य उच्चाधिकारियों—विदेश सेवा से जुड़े रनेन सेन (जिन्हें श्रीलंका संबंधी नीति और उससे जुड़े विवादों के लिए दोषी ठहराया जाता है), अतिरिक्त सचिव रंगराजन वासुदेवन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार मनटेक सिंह अहलूवालिया—का तबादला भी सुनिश्चित है।

जिन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला तय बताया जाता है, उनमें वित्त सचिव गोपी अरोड़ा व अतिरिक्त रक्षा सचिव एनएन वोरा शामिल हैं। कारण बोफोर्स घोटाले को ढंकने-मूंदने में इन दोनों की भूमिका काफी चर्चित हुई थी। गोपी राजीव गांधी के ग्रहण लगने के पूर्व तक उनके 'थिंक टैंक' के मुखिया माने जाते थे।

वित्त मंत्रालय में अरोड़ा के अलावा राजस्व सचिव सेनगुप्ता पर तो आंच आ सकती है, कुछ ही समयपूर्व धवन की अनुकंपा से छह लोगों को 'सुपरसीड' करके अध्यक्ष बनाये गये श्री थिड की भी रवान लगभग तय है।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय के सचिव बाब मुरारी का राष्ट्रपति वेंकटरमण के सचिव के रूप में तबादला पहले ही हो चुक है। लंदन से मीडिया विशेषज्ञ के रूप में जोरशोर से लाये गये करन थापर के बोरिया-बिस्तर बांधने की अफवाह भी पहल से ही गर्म है। इसी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव व 'इंडियन एक्सप्रेस' के पूर्व संपादक सुमन दुबे का हाल में अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, किंतु तलवार उनके पर भी लटक रही है। आकाशवाणी-दूरद के प्रमुखों और समाचार सेवाओं से जुड़ी हस्तियों की किस्मत का फैसला दूरबीनी जांच के पश्चात होने की पूर्ण संभावना है। इसका स्पष्ट संकेत राजमोहन गांधी के नवंबर के दूरदर्शन साक्षात्कार में मिला जिसमें उन्होंने सरकारी मीडिया के कामकाज के बारे में बेझिझक कहा था, "जिसने जैसा किया है, वह ही भरेगा।"

बरास्ते वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में गये विश्वनाथप्रताप सिंह यदि उसकी बारीक छानबीन और तत्पश्चात उसमें व्यापक फेरबदल करें, तो किसी को आश्च नहीं होना चाहिए। इसके बाद गृह मंत्रालय भी खंगाला जायेगा—विशेषकर उसकी ती गुप्तचर एजेंसियां सीबीआई, जिसमें अभी हाल तक प्रमुख रहे मोहन कात्रे की विवा ग्रस्त भूमिका उनकी राजनीतिक दखलंदाजी के तहत सुर्खियों में बनी रही थी। आईबी प्रमुख एमके नारायणन का जाना भी सुनिश्चित है। जानकार सूत्रों के अनुसार राजीव शासनकाल में आईबी का राजनीति करण इस हद तक हो गया था कि प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय बिना उसकी जानकारी और नारायणन की राय के नहीं करते थे। यह मजाक मशहूर था कि राजी गांधी के पास 'नारायण' को याद करने के लिए भले ही समय न हो किंतु नारायणन लिए हमेशा वे वक्त निकाल लिया करते।

यद्यपि रा—विदेशी मामलों की

एजेंसी है, किंतु उसके प्रमुख एके विषय में कहा जाता था कि उनकी गुप्तचरी संबंधी गतिविधियां भी थीं। इसलिए उनकी जांच-पड़ताल से नकार नहीं किया जा सकता।

कृषि मंत्रालय, विशेषकर आपूर्ति के चीनी-चावल आयात-निर्यात के घोटालों के कारण इसकी बारीक होने की पूर्ण संभावना है। चाहे वे से संबंधित लोग हों अथवा राज्य निगम के लोग। वाणिज्य मंत्रालय उसके उच्चधिकारी भी इसकी लपेट में सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के अनेक —खासकर जहां राजनीतिक तियां हुई हैं—की भी कड़ी जांच-परख सकती है।

दिल्ली प्रशासन का भी कायाकल्प ऐसा जानकार सूत्रों का मानना है। वर्नर रमेश भंडारी के दिन लदने के ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गिरेगी। सरकारिया आयोग की जिस को धवन व भगत गत जून से ठंडे

अरोड़ा

जी पार्थसारथी

में डलवाये हुए थे, उस पर अमल और दिल्ली प्रशासन का नया स्वरूप बनना है।

इस अपेक्षित भारी-भरकम फेरबदल समस्या यही उठेगी कि इतने रियों को कहां खपाया जायेगा? जब चर्चा एक उच्चाधिकारी से चली तो "अधिकांशतः ऐसे दागदार अफसरों के संबंधित राज्यों में वापस राजस्व के रूप में 'सूखे में मुंह मारने' भेज जाता है।"

इस तमाम फेरबदल के अलावा एक री की तरक्की सहित वापसी की सकती हैं। वे हैं घूरे (टकसाल) में टीकरे गिनते भूरेलाल। उल्लेखनीय है पी सिंह जब वित्तमंत्री थे तब भूरेलाल घोटालों को बेपर्द करने में पूर्ण भूमिका निभायी थी। भूरेलाल के बहुरेंगे, किंतु तमाम लोग शीघ्र बन जाएंगे।

—रंजना कक्कड़

में मशहूर था कि वे कभी अपने क्षेत्र में गये ही नहीं फिर भी जीत गये।" इसी प्रकार कटिहार से तीन बार सांसद रहे तारिक अनवर का कहना है कि जितना काम पिछले दस सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र में किया था उतना बिहार के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। फिर भी वे हार गये। "मेरी उपलब्धियों की बात सांप्रदायिकता के माहौल में स्पष्टतया बंटी मतदाताओं की जमात सुनने को तैयार ही नहीं थी।"

सांप्रदायिकता का यही माहौल और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद कांग्रेस को ले डूबा यह बात हर छोटा-बड़ा कांग्रेसी दोहरा रहा है। उनके अनुसार इस विवाद के कारण हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में चले गये और मुस्लिम वोट जनता दल और कम्युनिस्टों के। भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा असहमत हो बोले, "यदि इसी सांप्रदायिक आधार पर मतदान हुआ होता, तो जनता दल को उप्र और बिहार में इतनी सीटें न मिलतीं और हमारी सीटें कहीं अधिक होतीं।"

सांप्रदायिकता से नुकसान: मधुलिमये के अनुसार, "चुनावों के दौरान उत्तर भारत में दो धाराएं बहीं। एक, हिन्दुत्व की लहर जिसे 'रामायण' व 'महाभारत' सीरियलों ने बलवती बनाया। दूसरी धारा थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में राजीव विरोधी लहर और तथाकथित गठबंधन और तालमेल की। राजस्थान और गुजरात में ये दोनों धाराएं मिल गयीं और सीटों की बाढ़ ले आयीं। उत्तर प्रदेश व बिहार में हिन्दुत्व की धारा उपधारा बन गयी और राजीव विरोधी जनता दल धारा प्रमुख हो गयी। इसने मुस्लिम वोट अपने पक्ष में कर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम फैजाबाद लोकसभा सीट का था जहां एक ओर कांग्रेस थी जिसे विश्व हिंदू परिषद का पूर्ण समर्थन था तो दूसरी ओर भाकपा थी जिसे जनता दल का सहयोग प्राप्त था। और राम की इस नगरी में हार राम नाम की माला जपने वाली कांग्रेस की हुई।

जिस सांप्रदायिक माहौल को कांग्रेस उत्तर भारत में अपनी हार का मूल कारण मानती है उसे अधिकांश पर्यवेक्षक उसी का किया धरा मानते हैं। पहले से ही विवादग्रस्त बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने से लेकर ऐन चुनाव पूर्व निकटस्थ फैजाबाद से प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चुनाव अभियान आरंभ करने, रामराज्य लाने की बात करने और ९ नवंबर को मंदिर के शिलान्यास की अनुमति देने के पीछे पर्यवेक्षक कांग्रेस का सीधे-सीधे हिन्दू कार्ड खेलने का मंशा देखते हैं। यह दीगर बात है कि बाजी उलटते देख उसने कदम पीछे करने का प्रयास किया। किंतु यदि कांग्रेस के पहले कदम से मुसलमानों में असुरक्षाबोध और नाराजगी पैदा हुई, तो दूसरे कदम से हिन्दू, जो वैसे भी प्रायः एकजुट हो वोट नहीं डालते, बिफर गये। नतीजतन कांग्रेस को न माया (मुसलमान) मिली न राम (हिन्दू)।

कांग्रेस के तीन पारंपरिक मतदाता वर्ग—हरिजन मुस्लिम और ब्राह्मण में से मुस्लिम तो इस प्रकार अलग-थलग हुआ। दूसरे हरिजन वोट इस बार कांशीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने हथिया लिया। बावजूद इसके कि इसी संभावना से भयभीत हो कांग्रेस ने इस वर्ग (हरिजन) को रिझाने-पटाने में पिछले कुछ महीनों से कोई कोरकसर उठा नहीं रखी थी। मूल समस्या इसी चुनाव की नहीं है। लोकसभा की ३ और उप्र विधानसभा की १३ सीटों पर काबिज हो बसपा ने अपने को और अधिक ग्राह्य बना लिया है जो भविष्य में भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है।

उत्तर भारत में कांग्रेस की क्षति से जनता दल को मिला लाभ अपेक्षित था। अपेक्षित नहीं थी तो भाजपा की २ से ८८ सीटों की छलांग। यद्यपि परिणाम गत वर्ष के पालमपुर अधिवेशन में घोषित संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने और केंद्र बिंदु बनने के लक्ष्यों-नीतियों के अनुकूल था। किंतु इसकी अपेक्षा स्वयं भाजपा नेताओं को भी न थी। भाजपा की वर्तमान सफलता के महासचिव जगदीश प्रसाद माथुर ने तीन स्पष्ट कारण बताये—एक, पिछले दो-तीन सालों में किसानों, महिलाओं, युवाओं के मध्य काम कर उसकी जनाधार बढ़ाने की कोशिश। दो, सीटों का समुचित तालमेल, तीन, राजीव सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन आदि मुद्दों पर व्यापक जनअसंतोष। भाजपा के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने जोड़ा, "जब अन्य विपक्षी दल शिखर राजनीति में व्यस्त थे, तो हम संगठन को चुस्त-दुरुस्त कर जमीन की राजनीति कर रहे थे।" नतीजतन चुनाव घोषणा के समय मैदान में उतरने के लिए भाजपा की कदाचित सबसे अधिक तैयारी थी। रही-सही कसर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कांग्रेस को हिंदू कार्ड खेल लाभ न उठाने देने की उनकी सोची-समझी रणनीति ने पूरी कर दी।

वामपंथ को सबक: दक्षिणपंथ अर्थात भाजपा यदि अभूतपूर्व ढंग से लाभान्वित हुई है, तो वामपंथ अपने अपेक्षित विस्तार और विपक्षी सरकार का एकमात्र पैरोकार बनने की रणनीति में विफल रहा है। अपनी सीटों में इजाफा करने और उप्र बिहार और राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद भाजपा को सीमित-संकुचित करने का उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व सफलता के बावजूद केरल में भाजपा की चाणक्य-नीति से मिली पराजय वामपंथ के लिए एक नया सबक है।

कांग्रेस की क्षति भले ही हुई हो, किंतु राजीव गांधी के लिए नतीजे इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। गौरतलब है कि राजीव गांधी ही संपूर्ण चुनाव की धुरी थे। उत्तर में मिली करारी हार के लिए जिम्मेदार भी काफी हद तक राजीव विरोधी मुद्दे ही रहे। यह भी सच है कि चुनाव

परिणाम आने के पूर्व शायद ही कोई कांग्रेसी राजीव की सत्ता में वापसी का दिवास्वप्न देख रहा था। अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म था कि कोई पराजित प्रधानमंत्री के इटली भाग जाने की बात कर रहा था, तो कोई कांग्रेस के टूटने, भगदड़ मचने की अथवा उसके नेतृत्व में परिवर्तन होने की बात कर रहा था। हार तो हुई, किंतु अपेक्षित मार से राजीव गांधी और कांग्रेस दोनों ही बच गये।

कांग्रेस की सफलता: बचत का प्रमुख कारण एक तो दक्षिण के चारों बड़े राज्यों में मिली अभूतपूर्व सफलता रही। दूसरे उत्तर भारत में विभिन्न छत्रपों, दिग्गजों की हार राजीव का सबसे सुदृढ़ रक्षा कवच बन गयी। विद्रोह विस्फोट की आशंका जिन पांच पांडवों से थी—उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी, बिहार के जगन्नाथ मिश्र, मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह, गुजरात के माधव सिंह सोलंकी, महाराष्ट्र के शरद पवार—उनकी अपनी स्थिति निराशाजनक चुनाव परिणामों ने कमजोर कर दी। वर्षों के वनवास के पश्चात पुनर्स्थापित हुए दक्षिण के नये पुराने छत्रपों—गुंडूराव, वीरेंद्र पाटील, चेन्ना रेड्डी यहां तक कि महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान अंतुले—को फिलहाल पैर जमाने की चिंता अधिक है, राजीव को चुनौती देने की इच्छा-क्षमता कम। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के पश्चात संसद के केंद्रीय कक्ष में संसदीय दल के नये नेता चुनने के अवसर पर राजीव गांधी का जो स्वागत-समर्थन हुआ—वह किसी पराजित सेना नायक का सा न होकर रण बांकुरे जैसा था। तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य राजीव गांधी जिंदाबाद नारे जोर-शोर से लगाने में एक भी नेता कोताही नहीं बरत रहा था। अगुवाई वयोवृद्ध नेता रंगा और वर्षों से कोषाध्यक्ष रहे सीताराम केसरी कर रहे थे।

केसरी की इसी भूमिका पर टिप्पणी करते हुए एक सांसद बोले, "पार्टी कोषाध्यक्ष की यह आरती उतराई अकारण नहीं। उन्हें भलीभांति मालूम है कि जिस कोष के वे अध्यक्ष हैं, उसकी कुंजी राजीव गांधी के हाथ में है।" जानकार सूत्रों के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष राजीव गांधी ने अपनी मां से समूचे धन स्रोत को अपने कब्जे में रखने का सबक भलीभांति सीखा है। भीमकाय कांग्रेस को चलाते रहने के लिए जिन लाखों रुपयों की प्रति मास आवश्यकता है, वह केवल राजीव गांधी के पास है। उन्हें सर्वोच्च नेता बनाये रखने की यही वजह और विवशता है। धनकुबेर होने के अतिरिक्त राजीव गांधी कांग्रेस के फिलहाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें समूचे देश में जाना, पहचाना और माना जाता है। और यही उनके शीर्षस्थ नेता बने रहने का राज है।

कांग्रेस में सत्ताच्युत होने के बावजूद उथल-पुथल न मचने का एक अन्य कारण यह भी है कि भविष्य के प्रति उसने आशा नहीं खोयी है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद-पत्रकार एमजे अकबर का मानना है, "छह महीने के भीतर ही अपने अंतर्विरोधों और परस्पर संघर्षों के कारण वीपी सिंह की सरकार स्वयं हमारी सत्ता में वापसी प्रशस्त करेगी। कारण जिस सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विपक्ष सत्तासीन हुआ है, उसका जादू अधिक दिन नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जब तक हिंदू कुरआन और मुसलमान गीता नहीं बचायेगा तब तक भला नहीं होने वाला है।" कांग्रेसी सांसद पीएन सुकुल ने जोड़ा, "जूतमपैजार जनता दल में तो अभी से ही शुरू हो गयी है। उसके सहयोगियों के बीच दो महीने के अंदर शुरू हो जायेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना सुनिश्चित है और वामपंथी इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे।"

किशनलाल शर्मा ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। उनके अनुसार, "कांग्रेस फिलहाल इसलिए नहीं टूटी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। दूसरे उनकी उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि सरकार टूट जायेगी। किंतु जिस दिन कांग्रेसियों को पता चल गया कि यह सरकार स्थायी है और पांच साल तक चलेगी, तो सत्तासुख के आदी कांग्रेसियों का धैर्य का बांध भी टूटेगा और पार्टी भी।

राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा जहां तक स्थिर सरकार देने का प्रश्न है, तो यह अवश्य सही है कि वह अल्पमत सरकार है जिसके लिए बहुमत जुटाये रखना एक दुष्कर कार्य होगा। किंतु उसके सामने १९७९ का उदाहरण है जब आपसी सिर-फुटौवल के चलते जनता पार्टी सरकार टूट गयी थी। इस कालिख को धोने और अपने पैरों पर पुनः खड़ा होने में विपक्ष को दस वर्ष लगे थे। इस बार सरकार चलाने का दायित्व हर विपक्षी दल के ऊपर है, इसलिए सरकार तोड़ने की कालिख कोई भी अपने ऊपर लगाना नहीं चाहेगा। क्योंकि वर्तमान सरकार बहुदलीय और सर्वसम्मत के बलबूते हैं, इसलिए उसे स्थिर बनाये रखने की जिम्मेदारी भी सबकी होगी।

वर्तमान चुनाव विभिन्न पार्टियों के बदलते राजनीतिक समीकरण को ही नहीं, भारतीय मतदाताओं के इस बदले तेवर को भी उजागर करता है कि उसने कांग्रेस को हराया तो है, किंतु विपक्ष को जिताया भी नहीं। मध्य धारा की शासक पार्टी (राष्ट्रीय मोर्चे—जनता दल) के दायें-बायें उसने भाजपा और वाममोर्चे की बैसाखी लगा देश की राजनीतिक फिजा में नया आयाम ही नहीं जोड़ा हरेक की कथनी-करनी की बानगी लेने का बीड़ा उठाया है।

भविष्य कैसा है? कांग्रेस का सारा भविष्य इस समय विधानसभा चुनावों पर टिका हुआ है। प्रश्न यह है कि वह अपने निश्चित समय पर होंगे या विधानसभाएं समय से पूर्व भंग की जायेंगी? नवल किशोर शर्मा इसकी संभावना कम देखते हैं। क्योंकि ऐसा करने से मूल्य आधारित राजनीति की बात करने वाले सत्ता दल की साख पर आंच आयेगी। यदि यह मापदंड अपनाया गया कि जिन कांग्रेसशासित राज्यों में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, वहां की सरकारें भंग कर दी जायें, तो इसे विपक्षशासित राज्यों केरल व तमिलनाडु पर भी लागू करना पड़ेगा।

अधिकांश विधानसभा चुनाव आगामी मार्च में होने वाले हैं। यदि इस बीच जनता के फैसले को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों में लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व परिवर्तन करके चुस्त और साफ-सुथरी सरकार देने का कांग्रेस प्रयास करते देखी जाये और पार्टी संगठन अधिक गतिशील हो जाये, तो संभव है अगले तीन महीनों में वह अपने खोये जनाधार को काफी हद तक पा ले। इसके लिए १९८४ के लोकसभा चुनाव और १९८५ के विधानसभा चुनावों का उदाहरण सामने है। प्रथम में कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय मिली थी, किंतु पांच महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में जनता ने शासक दल कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था। किंतु कांग्रेस यदि उपरोक्त कदम उठाने में नाकाम रही, तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा।

इस तथ्य से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपरिचित नहीं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, "राजीव गांधी पिछले कुछ दिनों से जिस उन्मुक्त भाव से पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिल-जुल रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, उससे लगता है कि वे 'कोटरी (निहित स्वार्थों की टोली) की कोठरी' से आजाद हो गये हैं। यह एक बड़ा शुभ लक्षण है जो पार्टी को पुनः सुदृढ़ कर उसे शीर्ष पर पहुंचाने में पूर्ण सहायक होगा।"

वर्तमान चुनाव विभिन्न पार्टियों के बदलते राजनीतिक समीकरण को ही नही, भारतीय मतदाताओं के इस बदले तेवर को भी उजागर करता है कि उसने कांग्रेस को हराया तो है, किंतु विपक्ष को जिताया भी नहीं। मध्य धारा की शासक पार्टी (राष्ट्रीय मोर्चे-जनता दल) के दायें-बायें उसने भाजपा और वाममोर्चे की बैसाखी लगा देश की राजनीतिक फिजा में नया आयाम ही नहीं जोड़ा, हरेक की कथनी-करनी की बानगी लेने का बीड़ा भी उठाया है। कुछ भी हो, इस चुनाव से भारतीय राजनीति में नया मोड़ तो आया ही है, नयी राजनीतिक हलचलों की उर्वर भूमि भी तैयार हुई है।

—रंजना कक्कड़

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

सारा भविष्य
टका हुआ है।
मय पर होंगे
की जायेंगी ?
कम देखते हैं।
रत राजनीति
ख पर आंच
गया कि जिन
चुनावों में
है, वहां की
विपक्षशासित
लागू करना

व आगामी
च जनता के
सरकारों और
त्व परिवर्तन
कार देने का
पार्टी संगठन
है अगले तीन
को काफी हद
के लोकसभा
चुनावों का
को अभूतपूर्व
ने बाद हुए
शासक दल
कांग्रेस यदि
ी, तो उसका

शीर्ष नेतृत्व
रिष्ठ नेता के
दिनों से जिस
र्यकर्ताओं से
रहे हैं और
क वे 'कोटरी
ी' से आजाद
जो पार्टी को
चाने में पूर्ण

यों के बदलते
ी, भारतीय
भी उजागर
तो है, किंतु
य धारा की
ल) के दायें-
की बैसाखी
ा आयाम ही
ी बानगी लेने
इस चुनाव से
आया ही है,
र भूमि भी

ना क
व के सा

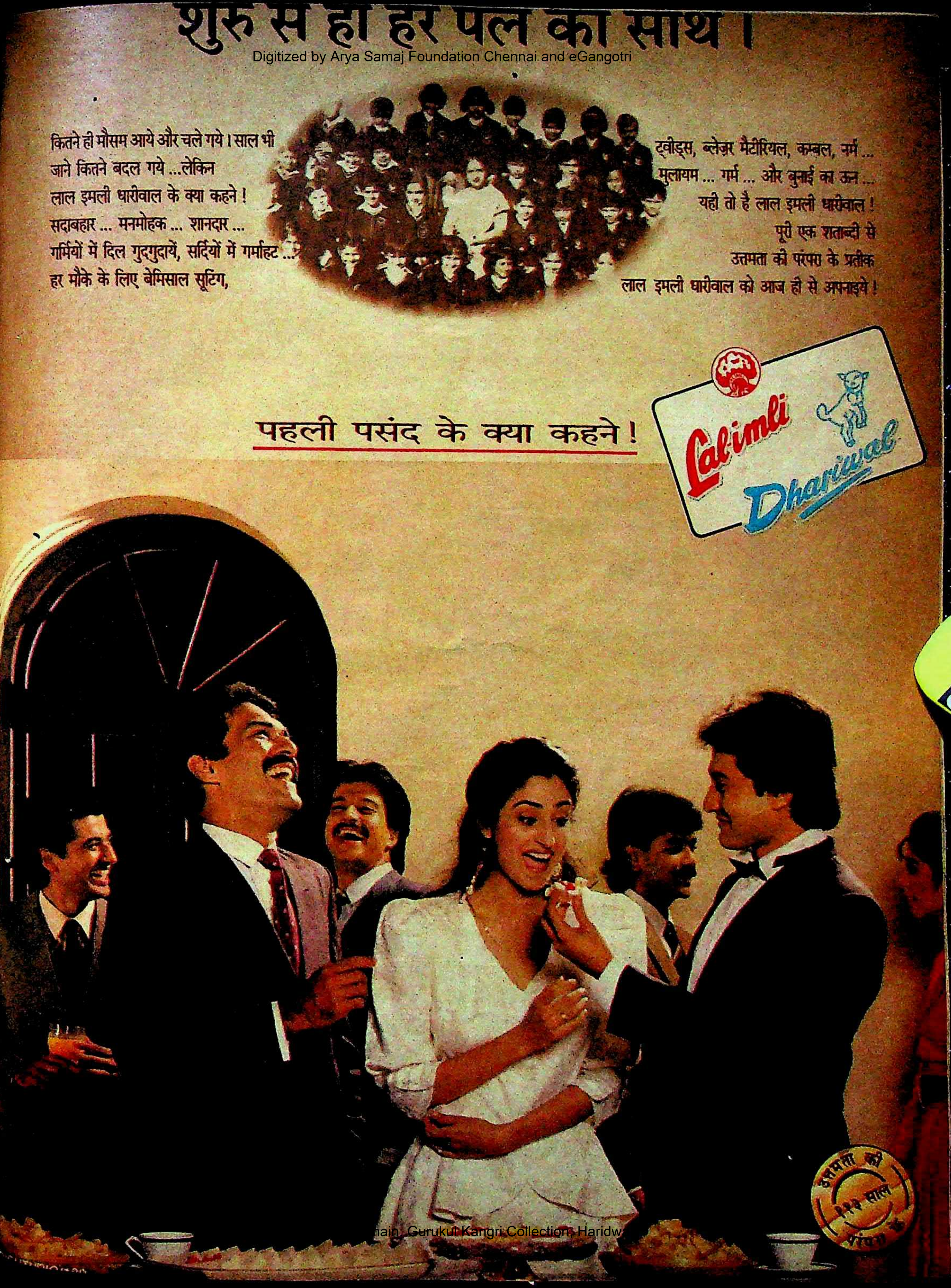
शुरु से ही हर पल का साथ।

कितने ही मौसम आये और चले गये। साल भी
जाने कितने बदल गये ...लेकिन
लाल इमली धारीवाल के क्या कहने!
सदाबहार ... मनमोहक ... शानदार ...
गर्मियों में दिल गुदगुदायें, सर्दियों में गर्माहट ...
हर मौके के लिए बेमिसाल सूटिंग,
ट्वीड्स, ब्लेज़र मैटीरियल, कम्बल, नर्म ...
मुलायम ... गर्म ... और बुनाई का ऊन ...
यही तो है लाल इमली धारीवाल!
पूरी एक शताब्दी से
उत्तमता की परंपरा के प्रतीक
लाल इमली धारीवाल को आज ही से अपनाइये!

पहली पसंद के क्या कहने!

Lal·imli
Dhariwal

उत्तमता की [illegible] साल परंपरा के

main. Gurukul Kangri Collections Haridw

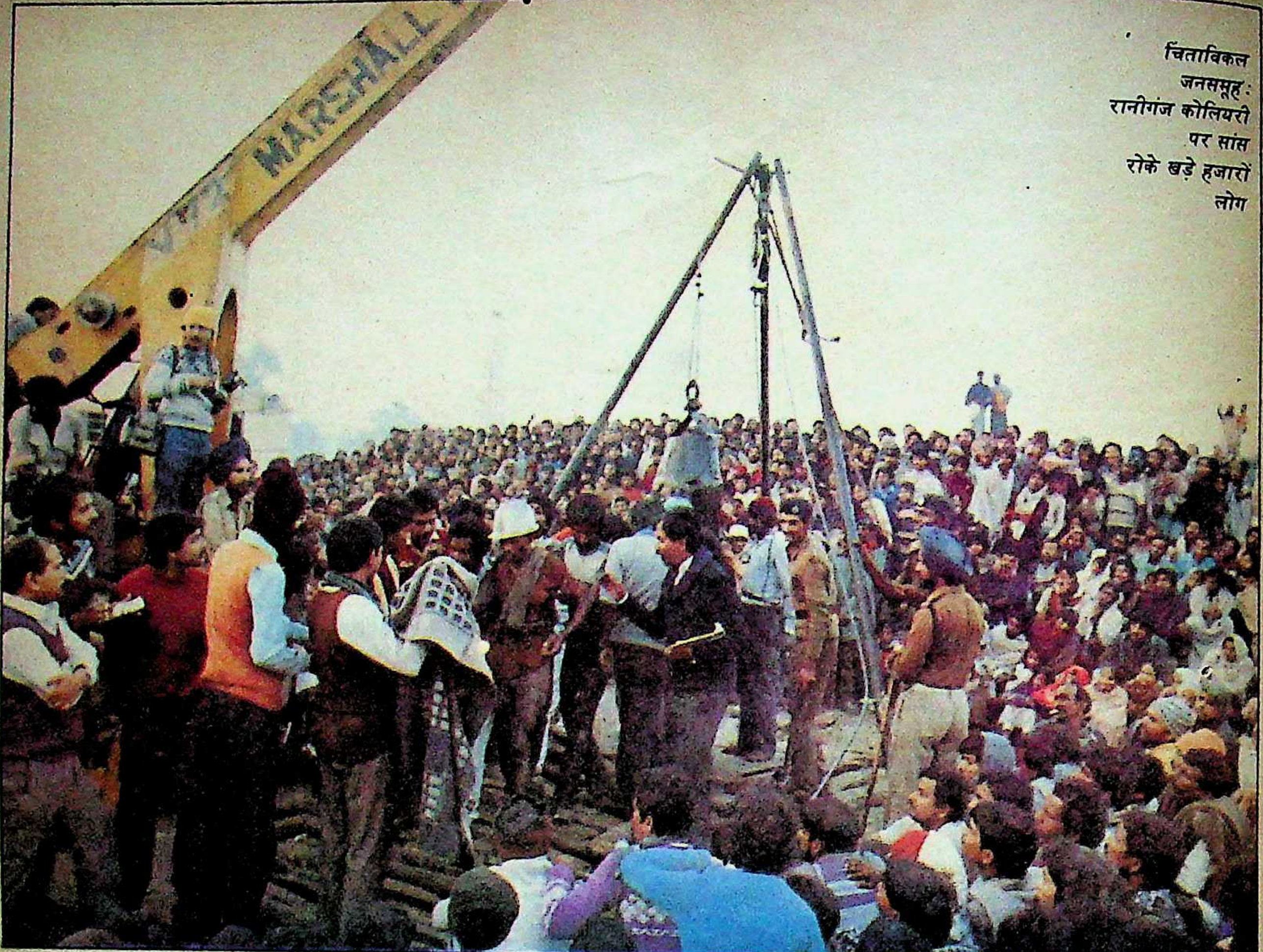

चिंताविकल जनसमूह: रानीगंज कोलियरी पर सांस रोके खड़े हजारों लोग

बयासी घंटे जिंदगी और मौत के बीच

कोल इंडिया द्वारा संचालित महावीर कोलियरी डेढ़ सौ वर्ष से ज्यादा पुरानी है। भारत सरकार द्वारा गठित कई समितियां इसे खतरनाक घोषित कर चुकी हैं, लेकिन कोल इंडिया अब भी यहां काम जारी रखे है।

१२ और १३ नवंबर की संधिवेला में यानी रात १२ बजे से सुबह ४ बजे तक की पाली का काम शुरू हुआ। २२२ मजदूर खान के अंदर गये। जमीन से लगभग ३०० मीटर नीचे काम चल रहा था।

अचानक सुबह ४ बजे के करीब कुछ मजदूरों ने पानी के बहने का कल-कल शब्द सुना, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। कोयला खान के मजदूर इस आवाज को अच्छी तरह पहचानते हैं। चौकन्ने सब हुए, भागे भी, पर कुछ निकल पाये और कुछ फंसे रह गये।

रिसते हुए पानी ने थोड़ी देर बाद जलधार का रूप धारण कर लिया, जिसका स्तर क्रमशः बढ़ने लगा। खान में जहां-तहां काम कर रहे मजदूर भागकर २२ और २३ नंबर की गैलरी में पहुंचे क्योंकि यह स्थान काफी ऊंचा था। कुछ लोग हिम्मत हारने लगे पर दो-एक ने हिम्मत दिखायी। आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने फोन पर खान प्रबंधकों से बातचीत करने की कोशिश की। गनीमत थी कि फोन की लाइन चालू थी और ऊपर यह खबर पहुंच गयी कि फंसे हुए मजदूर अमुक जगह पर हैं। साथ ही मजदूरों को भी यह तसल्ली हो गयी कि उनको निकालने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

ईसीएल के प्रबंधकों ने समस्या के हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया। मजदूरों को निकालना जितना जरूरी था, उतना ही यह भी कि इस बीच उनके पास खाने के पैकेट, पीने का पानी वगैरह भिजवाया जाये और जरूरत पड़ने पर आक्सीजन सिलिंडर भी भेजे जायें। १३ नवंबर की शाम ५ बजे फंसे हुए लोगों में से शालिग्राम सिंह की कमजोर-सी आवाज सुनायी दी, "खाने से ज्यादा जरूरी, आक्सीजन है हमारे लिए।"

तुरंत एक और बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। खाना और आक्सीजन सिलिंडर भिजवाने की व्यवस्था की गयी। खाने के पैकेट तो २४ घंटे बाद ही पहुंच पाये।

इस बीच ये प्रयास भी जारी रहे कि पानी की ऊंचाई बढ़ने न पाये और जल्द-से-जल्द जमा हुआ पानी बाहर निकाला जाये। पांच पंप लगातार पानी निकालने का काम करते रहे। बिजली की सप्लाई बनाये रखी गयी। इस बीच संदेश आते-जाते रहे। इनमें आनंदी पांडेय का यह

संदेश भी था कि जल्द ही सबको बाहर न निकाला गया, तो जल समाधि लेने से पहले घिरे हुए लोग एक दूसरे का गला दबा कर मर जायेंगे। प्रबंधक वर्ग और यूनियन के नेताओं ने मजदूरों को थोड़ा धीरज और रखने की सलाह दी।

इस बीच टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से सारे देश में इस दुर्घटना का समाचार फैल गया। सब तरफ हलचल मच गयी। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि २० वर्ष पूर्व जर्मनी में हुई ऐसी ही एक दुर्घटना में अमल में लायी गयी तरकीब आजमायी जाये।

इसके मुताबिक रिगों की मदद से ७० सेंटीमीटर मोटे दो पाइप डालने के लिए खुदाई का काम चालू रखा गया। दूसरी तरफ ईसीएल ने अपनी मोबाइल वर्कशाप की मदद से घटनास्थल पर ही कैप्सूल के आकार में लोहे का एक ढांचा तैयार कराया। यह तय हुआ कि इस कैप्सूल को लोहे की केसिंग में रखकर पाइप में उतारा जाये, ताकि ऊपर की दोमट मिट्टी की परतें लोहे के ढांचे पर या मजदूरों पर गिरने का खतरा न रहे।

यह सब काम पूरा होते १४ नवंबर भी बीत गया और १५ नवंबर की शाम हो आयी। तब घोषणा की गयी कि रात १२ बजे के बाद उद्धार कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा। मजदूरों के रिश्तेदार और आसपास के हजारों मजदूर रात नौ बजे से वहां भीड़ लगाने लगे। इनके साथ ही फोटोग्राफरों, संवाददाताओं और समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी काफी बड़ी संख्या में जमा हो गये।

रात के एक बजे के लगभग लोहे की केसिंग गर्त में उतारी गयी। बोट से ऊपर तीन लोहे के बड़े-बड़े बीम थे, इन्हीं पर पुली और क्यूबिकल टंगे थे। पुली पर से होकर मोटे-मोटे लोहे के तार आये थे और इन तारों के सहारे लटका था वह कैप्सूल, जिसकी लंबाई ७३ इंच और व्यास १९ इंच था। इस कैप्सूल में ईसीएल के खान विशेषज्ञ तथा डिपुटी चीफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिह गिल स्वयं नीचे गये और नीचे जाकर उन्होंने एक के बाद एक ६५ मजदूरों को ऊपर भेजा।

रात भर ठंड में ठिठुरते लोग खड़े यह देखने की प्रतीक्षा करते रहे कि इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है। १६ तारीख को रात्रि २.४५ पर आरंभ हुआ उद्धार कार्यक्रम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुबह ९.४५ पर खतम हुआ। सबसे पहले शालिग्राम सिह बाहर आया। पूरे ६५ मजदूरों के बाहर निकलने पर अंत में जसवंत सिह गिल बाहर आये। उनके साहस और शौर्य की जितनी तारीफ की जाये, कम है। अपनी जान खतरे में डालकर इस इंजीनियर ने बिहारी और बंगाली मजदूरों की जान बचाकर राष्ट्रीय एकता का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

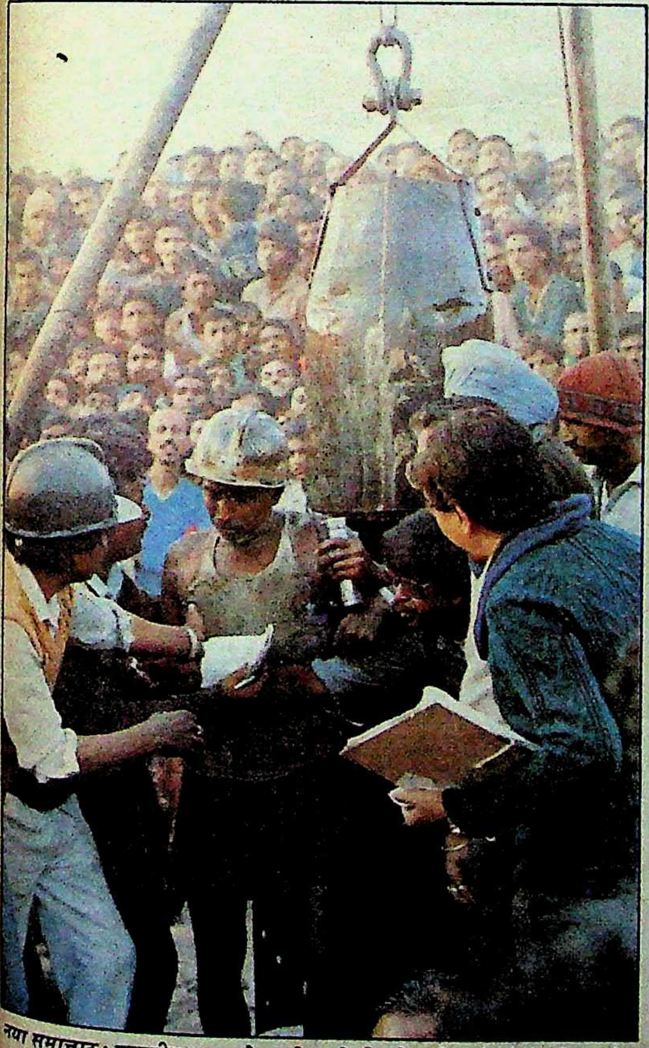

नया समाचार: महावीर खदान से सबसे पहले निकले श्रमिक से लोगों की वार्ता

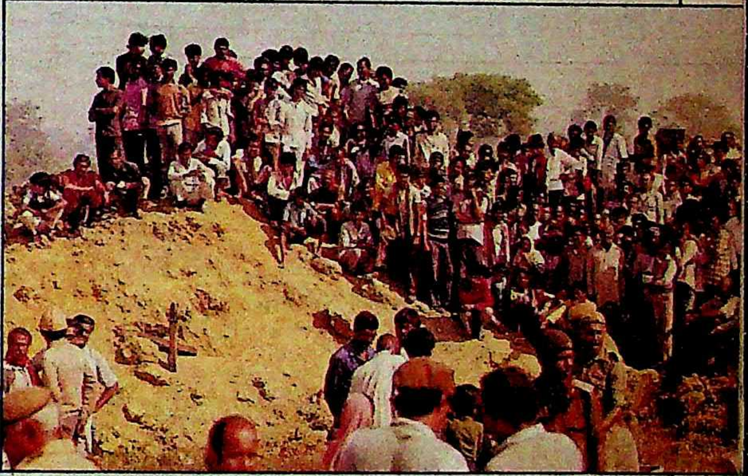

जीवन की प्रतीक्षा: महावीर कोलियरी में फंसे मजदूरों के उद्धार का इंतजार

८२ घंटों से भी अधिक समय तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे ये खान-श्रमिक जब बाहर आये, तो परिवारजनों और मित्रों-परिचितों को देखकर मुस्कराये तो जरूर, परंतु वे इतने थके और बेहाल थे कि उनको सीधे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस पूरी अवधि में उनमें से कोई न सोया था, न सोने का मौका दिया था उन्होंने एक दूसरे को। जबरन ही सही, पर कभी वे आपस में हंसी-मजाक करते रहे, कभी गाते रहे। बाद में तो उनके मनोरंजन के लिए टेपरिकार्डर भी नीचे भेज दिया गया था।

१९७५ की चसनाला दुर्घटना के बाद जिसमें ३७२ लोगों को जलसमाधि लेनी पड़ी थी, महावीर कोलियरी की यह दुर्घटना अपने ढंग की सबसे भीषण दुर्घटना थी। दुर्घटना होने पर किया गया वैज्ञानिक प्रयास अनूठा था, यह भी सच है। त्रासदी टल गयी, यह सौभाग्य की बात है, परंतु ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं कि ऐसी पुरानी कोयला खदानों में आखिर काम बंद कब होगा? कब तक मजदूरों और मेहनतकशों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? खानों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद यह जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जनकल्याणकारी राष्ट्र की हमारी परिकल्पना आखिर कब साकार होगी?

छाया: अशोक बोस

—चंदन नियोगी

एक किलो सागर स्किम्ड मिल्क पाउडर आपको देता है
साढ़े दस लीटर स्किम्ड मिल्क.
इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे यूं ही पीना पसंद करेंगे.
या फिर आप इससे गुलाबजामुन, आइसक्रीम, दही,
खीर, रसगुल्ला, कस्टर्ड, मिल्कशेक भी बना सकते हैं.
और हां, चाय और कॉफ़ी भी.
सागर. दूध का सागर.

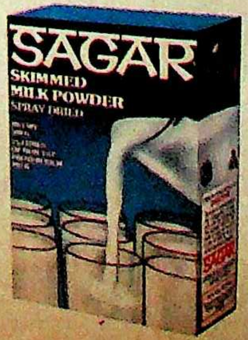
SAGAR
SKIMMED
MILK POWDER
SPRAY DRIED

सागर
स्किम्ड मिल्क
पाउडर
५०० ग्राम के
पैक में
उपलब्ध.

बिक्री व्यवस्था - गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आणंद, गुजरात. OPERATION FLOOD

ASP-SSMP-357/88 HIN

हरियाणा

आंधी के पहले की चुप्पी

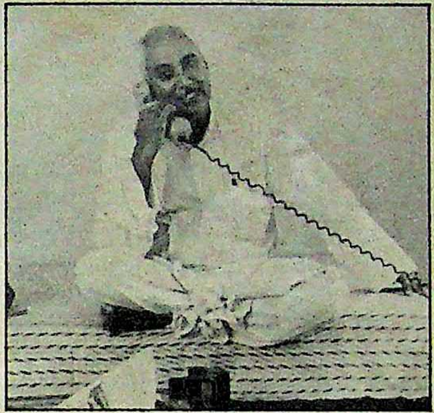

मौका और मुस्तैदी : ओम प्रकाश चौटाला

उथलपुथल के साथ गुजरे वर्ष १९८९ के आखिरी माह का पहला दिन यदि पूर्ववर्ती शासक दल के लोगों द्वारा 'मीर जाफर' करार दिये जाते रहे वीपी सिंह को 'काव्यात्मक न्याय' दे गया, तो हरियाणा की धरती के जाटपुत्र की राजनीतिक छवि में भी चार चांद लगा गया। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के नाते कोई बड़ी हस्ती नहीं थे। लेकिन उस पद पर रहते हुए जब वे विपक्षी एकता के सफल सूत्रधार बन गये, तब देशवासियों के दिल-दिमाग पर छा गये। इसी कारण वे प्रधानमंत्री पद के 'सर्वसम्मत पात्र' के रूप में उभरे। पर इससे भी आगे बढ़ उन्होंने अपनी दरियादिली दिखायी और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री-पद दे स्वयं राष्ट्र का ताऊ बनना बेहतर माना।

पहली दिसंबर को सेंट्रल हाल में संसदीय बोर्ड की बैठक में जब वे धन्यवाद-प्रकाश की औपचारिकता निभाने के लिए खड़े हुए, तो मौजूद चेहरों पर आशंका की रेखाएं उभर आयीं। क्या बाड़ खेत को चर जायेगी? वे चेहरे तब और चमत्कृत हो उठे, जब देवीलाल ने हाथ में आया प्रधानमंत्री-पद राष्ट्रीय स्तर पर उसके पूर्व स्वीकृत पात्र, वीपी सिंह की तरफ बढ़ा दिया। इस निजाम के कट्टर विरोधी चंद्रशेखर ताकते रह गये और वह बुजुर्ग नेता आम लोगों के दिल में अपना ऊंचा स्थान बनाने में सफल हो गया। अगली दुपहरी आयी और हरे मुरेठावाले दोहरी काठी के जाट नेता ने उपप्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली।

देवीलाल की नियुक्ति ने हरियाणा में घटनाक्रम को तेज कर दिया। फटाफट प्रदेश जद विधायक दल की बैठक बुलायी गयी और 'ताऊ' के ज्येष्ठ पुत्र ओमप्रकाश चौटाला नेता चुन लिये गये। राज्यपाल एचए बरारी चंडीगढ़ से उड़कर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ देवीलाल का इस्तीफा मंजूर किया और दूसरी तरफ हरियाणा भवन के सहन में चौटाला को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

हालांकि चौटाला का चुनाव आधिकारिक तौर पर 'निर्विरोध' बताया गया, पर इसके विरोध की खबरें शपथ-ग्रहण समारोह में भी मिलती रहीं। वास्तव में नयी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के टेलीफोन पहली दिसंबर की सुबह से ही घनघनाते रहे और पार्टी विधायकों से संपर्क साधकर उन्हें अगली सुबह होनेवाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा जाता रहा।

चौटाला भी अब कोई मौका खोना नहीं चाहते थे। कृपाराम पुनिया के नेतृत्व में पाला बदलनेवाले चार मंत्रियों ने चुनाव के पूर्व इस्तीफा देकर जाट प्रदेश की राजनीति में एक तूफान उठा दिया था। पांच और विधायकों ने विद्रोहियों के साथ ही अपनी किस्मत जोड़ ली। इन सबके बारे में फौरन कदम उठाये गये। परमानंद, लक्ष्मण कंबोज, हरि सिंह सैनी, दुर्गादत्त अत्रि, वासुदेव शर्मा, योगेश शर्मा, मुन्नीलाल और तैयब हुसेन को छह वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिये जाने से बाप की कुरसी बेटे को मिलना आसान हो गया।

हरियाणा में भाजपा-जद गठबंधन के ८५ विधायक हैं। इनमें भाजपा के १८ विधायक हैं और भाकपा तथा माकपा के एक-एक। शेष ६५ में से ९ पार्टी से निकाल दिये गये। बाकी बचे ५६ जद विधायकों में से ४४ ने चौटाला को समर्थन दिया, जबकि १२ बैठक में शामिल नहीं हुए। चौटाला के पदग्रहण समारोह में हालांकि अटलबिहारी वाजपेयी और कृष्णलाल शर्मा मौजूद थे फिर भी पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल की सहभागी भाजपा के रुख के बारे में काफी विभ्रम बना रहा। एक तथ्य तो यह था कि संसदीय चुनावों ने हरियाणा में भाजपा के शहरी समर्थन में आयी भारी कमी को उजागर किया है। दूसरे, चौटाला के अड़ियल तथा दबंग रुख के कारण ऐसा समझा गया कि भाजपा मंत्रिमंडल में शिरकत करना नहीं चाहती थी। कहा जाता है कि भाजपा का एक ताकतवर गुट इस दृष्टिकोण पर दृढ़ था कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार को बाहर से ही समर्थन दिया जाये, उसमें शामिल कदापि न हुआ जाये।

परेशानियों के आसार: कुछ भी हो, हरियाणा की चौटाला सरकार को परेशानियों का सामना करना ही है। एक तो बेटे को बाप जैसा समर्थन और सम्मान प्राप्त नहीं है। दूसरे, सबको समेट कर ले चलने में देवीलाल को पिछले दिनों जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे अब भी बनी हुई हैं। चौटाला पहले से चाहते थे कि देवीलाल लोकसभा में जायें और केंद्र सरकार की व्यवस्था संभालें। यही बात दिमाग में रखकर वे चंद्रशेखर से संपर्क बनाये रहे। ताऊ के प्रधानमंत्री पद से अलग रहने और उपप्रधानमंत्री-पद ग्रहण करने के पीछे दो ही खिलाड़ी रहे—एक चौटाला, दूसरे वीपी सिंह।

विजय के उल्लास के साथ सतह पर जो शांति दिखने लगती है, वह हरियाणा में भी दिख रही है। लेकिन यह स्थायी शांति नहीं, बल्कि आंधी के पूर्व की खामोशी है। अनुज रणजीत सिंह, चौटाला को मुख्यमंत्री की कुरसी हासिल करने से भले न रोक पाये हों, लेकिन इस बात के तमाम आसार हैं कि उनकी चौटाला विरोधी जंग जारी रहेगी। राज्य में नेतृत्व-परिवर्तन से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। पार्टी के एक नेता का कहना है कि जद विधायकों के टूटने-बिखरने के दिन बहुत करीब हैं, असंतोष बढ़ रहा है। लोकसभा चुनावों में भजनलाल और बंसीलाल भले कम वोटों से जीते हैं, पर आनेवाले दिनों में कांग्रेस-इ का वर्चस्व बढ़ना ही है। देवीलाल मंत्रिमंडल से विद्रोह कर हटे डा० पुनिया बताते हैं कि उनको और बहुत से अन्य मंत्रियों को, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, प्रदेश जद अध्यक्ष चौटाला ने अपमानित किया है। दूसरी ओर उनके भ्रष्टाचार और कोश के घालमेल से सर्वत्र क्षोभ व्याप्त है। डा० पुनिया, रनजीत सिंह के करीबी साथी हैं। केंद्र में जद सरकार बनने की संभावना के साथ ही खबर उड़ी कि चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। इस खबर को फिलहाल दबाने के लिए देवीलाल ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा भंग कर दी जायेगी। चुनाव हो गये, पर विधानसभा भंग नहीं हुई और चौटाला मुख्यमंत्री बना दिये गये। अब पता चला है कि पुनिया ने हरियाणा सरकार से संबंधित कुछ दस्तावेज कुछ केंद्रीय जद नेताओं को दे रखे थे। इसीलिए उन्होंने मंत्रिपद छोड़ने के बावजूद पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, पर देवीलाल के उप्रधानमंत्री बन जाने से स्थिति ही बदल गयी। डा० पुनिया और उनके समर्थक निरुपाय हो गये। लेकिन आखिरी फैसला अभी होना है। पुनिया के इस्तीफा से जहां जाट मतदाता एकजुट हुए हैं, वहीं गैरजाट—खासकर अनुसूचित जातिवाले—बिदके हैं और इसमें संदेह नहीं कि डा० पुनिया एक महत्वपूर्ण धुरी बनेंगे।

—आरके मिश्र

किस्सा मियां-बीवी का

प० बंगाल के मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र में चर्चा का मुद्दा भ्रष्टाचार व महंगाई की अपेक्षा मियां-बीवी की परस्पर विरोधी आस्था, विश्वास को लेकर रहा। कारण, वहां के पूर्व लोकसभा सदस्य नारायन चौबे को भाकपा ने इसलिए टिकट नहीं दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी गौरी चौबे कांग्रेस प्रत्याशी थीं। श्रीमती चौबे मतदाताओं से शिकायत करती घूम रही थीं, "माकपा— जिसकी शरण में भाकपा चुनाव लड़ रही है—मेरे पति व बेटों को आतंकित किये हुए है और कांग्रेस ही उनकी रक्षा कर सकती है।" उनका यह भी दावा था कि उनके पति ही वाममोर्चा के एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे। उनके नामांकनपत्र भरने के बाद इस प्रश्न पर कि यदि भाकपा चौबे को टिकट दे दे, तो क्या वह अपना नाम वापस ले लेंगी, उनका जवाब था, "मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा संघर्ष वाममोर्चा के खिलाफ है।" भाकपा के अनुसार चौबे ने अपनी पत्नी के कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर खुद चुनाव न लड़ने को कहा था। मियां-बीवी के इस छत्तीसी रिश्ते पर ही भाकपा को अपने उपमहासचिव इंद्रजीत गुप्त को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा था।

सबसे ऊंचे

नवीं लोकसभा के लिए चुने गये ५२९ सांसदों में धंधुका निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रतीलाल वर्मा सबसे ऊंचे हैं। उनकी लंबाई ६ फुट ५ इंच है। वर्मा का दावा है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी उनसे उन्नीस हैं, क्योंकि वे अमिताभ से ३ इंच लंबे हैं।

नतीजा ठन-ठन गोपाल

शौकिया उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरने से रोकने की निर्वाचन आयोग की कोशिशों के बावजूद वीटीआर वीरप्पा गाउंडर ने लोकसभा व तमिलनाडु विधान सभा चुनावों में २५ बार हारने के बावजूद इस बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी व पलानी (तमिलनाडु) विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आये। ४५ वर्षीय चेंगई अन्ना जिला स्थित अच्छरपक्कम के कृषक वीरप्पा को, गोकि अपनी कामयाबी के बारे में कोई भ्रम नहीं था, फिर हार ही नसीब हुई। वे चुनाव लड़ने का एक भी मौका नहीं चूकते। खासकर वीआईपी क्षेत्रों से। उनके प्रख्यात प्रतिद्वंद्वियों में श्रीमती इंदिरा गांधी शामिल थीं।

पसंद अपनी-अपनी

मद्रास में रहनेवाले राजस्थानी दंपती तमिलनाडु से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अनेक वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार ४५ वर्षीय मानकचंद नाहर उत्तरी मद्रास से खड़े हुए, तो उनकी पत्नी (सुशीला नाहर) दक्षिणी मद्रास से फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला के मुकाबले खड़ी थीं। मियां-बीवी के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र तो अवश्य थे, किंतु दोनों का चुनाव चिह्न एक ही था—उनके गृह राज्य का पारंपरिक जहाज ऊंट, जो उन्हें विजयश्री दिलाने में इस बार भी कामयाब नहीं हुआ।

परदादा की पसंद

हरियाणा को कदाचित न सिर्फ देश का सर्वाधिक वयोवृद्ध मुख्यमंत्री (देवीलाल) बनाने, बल्कि सर्वाधिक वयोवृद्ध मतदाता देने का अवसर भी तब प्राप्त हुआ। रोहतक जिले के पकसमा गांव के ११० वर्षीय फूल सिंह गत २२ नवंबर को अपने ३५ वर्षीय पोते के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचे। शरीर से श्लथ, किंतु दिमाग से चौकस फूल सिंह से मतदान के पूर्व जब पूछा गया कि वे किसे वोट देंगे, तो चट बोले, "मैं उसी को वोट दूंगा जो मेरे बच्चों की भलाई करेगा।" पांच पीढ़ियों के २५ सदस्यों वाले परिवार के अगुवा फूल सिंह आजादी के बाद के सभी (९) चुनावों में मतदान कर चुके हैं।

गाजे-बाजे सहित राजे-महाराजे

कांग्रेस ने समाजवाद के नारे पर राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स तो बंद कर दिया था, किंतु उनसे राजनीतिक रिश्ता तोड़ने की उसकी कदाचित कतई मंशा नहीं थी। इसीलिए तो इस बार उसने रेलमंत्री सिंधिया के अलावा मप्र के सात राजपरिवारों के उम्मीदवारों—महेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह जूदेव, प्रवीनकुमारी देवी, विजयप्रताप सिंह, पुष्पादेवी सिंह, शिवेंद्र बहादुर सिंह और दिगविजय सिंह—को खड़ा किया था। इसी प्रकार उड़ीसा से १० राजा-महाराजा खड़े थे। मसलन धेनकेनाल रियासत के राजा केपी सिंह देव धेनकेनाल संसदीय क्षेत्र से पुनः इंका प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, तो धारकाट के महाराज एएन सिंह देव अक्सा संसदीय क्षेत्र से जनता दल के प्रत्याशी बने। परलाखेमुंडी के राजा गोपीनाथ गजपति देव बरहमपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। जनता दल का टिकट पाने में असफल रहने पर बोलनगीर के राजा आरआर सिंह देव भाजपा के टिकट पर बालेनगीर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बने। कालाहांडी के शाही परिवार के तीन व्यक्ति भी जनता दल टिकट की जुगाड़ न होने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये। इस क्षेत्र में युवराज उदित देव को भाजपा ने टिकट दिया।

जनता दल भी राजाओं को प्रत्याशी बनाने में पीछे नहीं रहा। जद टिकट पर राजा एसएनएस माहपात्र कटक से प्रत्याशी थे, तो भुवनेश्वर सीट" से राजा रामचंद्र देव।

फरियाद दूल्हा-दुल्हन की

उम्मीदवार चुनाव प्रचार का एक भी मौका हाथ से खोना नहीं चाहते। चाहे वह घर हो, बाहर हो, सड़क हो, गली हो, परिचित हो, अपरिचित हो। लेकिन मदुरै के इंका उम्मीदवार एजीएस रामबाबू ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए शादी के मौके को भी चुनाव-प्रचार का रंग दे दिया। गत नवंबर के प्रथम पखवाड़े में उनकी शादी हुई और शादी का विधि-विधान पूरा होने के बाद वे मंच पर जाकर खड़े हो गये और आमंत्रित लोगों से इंका को वोट देने का अनुरोध किया। वधू ने हाथ का पंजा दिखाकर अपना समर्थन अपने पति के प्रति व्यक्त किया और वोट का दहेज मांगा। शादी के समारोह में भी रामबाबू ने कई जगहों पर वोट देने की अपील की।

अंतिम कार्य

जिसकी जिंदगी का पहला और अंतिम कार्य राजनीति हो उसके लिए चुनाव भी जीवन-मरण का प्रश्न होता है। खासकर तब जब व्यक्ति सशस्त्र क्रांति को त्याग संसदीय प्रणाली अपनानेवाला वामपंथी नेता-कार्यकर्ता हो। इसकी ज्वलंत मिसाल वामपंथी मोर्चा शासनवाले केरल के कोचीन में गत २२ नवंबर के मतदान के अवसर पर देखने को मिली जब भाकपा के स्थानीय कमेटी सदस्य ३५ वर्षीय सीआर सोमान की, मतदान किये जाने के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद, मतदान केंद्र में ही मृत्यु हो गयी।

कुरुक्षेत्र के महाभारत संग्राम में भाई-भाई जहां आमने-सामने थे वहीं मौजूदा चुनावी महाभारत में अनेक दिलों, रिश्तों की टक्कर हुई है। ऐसा ही एक प्रकरण गुना (मप्र) की भाजपा उम्मीदवार राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उनके पुत्र रेलमंत्री माधवराव सिंधिया के संबंधों में उजागर हुआ। श्रीमती सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने माधवराव के दाहिने हाथ महेंद्र सिंह को खड़ा किया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में जहां-जहां राजमाता की सभा

हुई, अगले ही दिन उनके प्रतिद्वंद्वी के मुख्य समर्थक-प्रचारक उनके पुत्र ने उससे बड़ी सभा-रैली की। मजे की बात तो यह है कि भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही शिवपुरी की उस 'बंबई कोठी' में, विश्राम करते थे जो माधवराव सिंधिया के स्वामित्व में है।

सर्वाधिक उम्मीदवार

५२५ लोकसभा सीटों और ५ राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों में लगभग ७००० उम्मीदवारों ने भाग लिया। मात्र भिवानी (हरियाणा) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां से मुख्यमंत्री देवीलाल भी उम्मीदवार थे, १४१ लोग चुनाव मैदान में थे। यहां के अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न देने में निर्वाचन आयोग को दांतों तले पसीना आ गया था। इस क्षेत्र के लिए तैयार मतपत्र, जो किसी समाचारपत्र के पृष्ठ के बराबर थे, अनेक युवा मतदाताओं के लिए ऐसे संग्रहणीय वस्तु बन गये थे जिसे मतपेटी में डालने की अपेक्षा उन्होंने अपनी जेब के हवाले करना बेहतर समझा।

भारी खर्च

संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव कराने पर लगभग २०० करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है। ५२९ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्र तैयार करने पर ही मात्र २.९६ करोड़ रु० खर्च हुए हैं। एक मतपेटी पर ४०५ रु० खर्च होते हैं। इस मद में २४.१४ करोड़ रु० लगे हैं। विशेष स्याही, जो मतदाता की उंगली पर लगायी गयी, फी सीसी ११ रु० में आयी थी। मतदान केंद्र में प्रयुक्त अन्य स्टेशनरी पर १२ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मतदान केंद्र की प्रबंध टोली पर रोजाना ५.९८ करोड़ रु० व्यय हुए हैं।

रिकार्ड निर्दलीय

अब के लोकसभा चुनाव मैदान में रिकार्ड निर्दलीय उम्मीदवार—५००० खड़े हुए। उनमें गिनती के ही (कुल १६ के) सर पर सफलता का सेहरा बंधा। किंतु यह एक रहस्य बना हुआ है कि इतने अधिक आशावादियों ने अपना धन, समय और सुख-चैन गंवाना क्यों पसंद किया? १९७७ में ११७९ निर्दलीयों में मात्र ९ जीते थे। १९८० में २२९० निर्दलीय उम्मीदवारों में भी विजेताओं की संख्या वही अर्थात ९ रही जबकि १९८४ में ३८७८ में महज ५ कामयाब हुए थे। इस बार के जाने माने निर्दलीय उम्मीदवारों में डा० शिवराम कारंत कारवार (कर्नाटक) से पर्यावरण मंच से पूर्व विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन दक्षिण मद्रास से खड़े हुए थे। इतने अधिक निर्दलियों के खड़े होने से निर्वाचित आयोग के सामने उन्हें अलग-अलग चुनाव चिह्न देने की भी विकट समस्या थी। कुछ चुनाव चिह्न तो गजब के थे। मसलन एआईएस-एसएफ अध्यक्ष अतिंदर पाल सिंह, जो पटियाला से चुनाव लड़ रहे थे, को ताला और चाभी चुनाव चिह्न मिला। उल्लेखनीय है कि वे श्रीमती गांधी की हत्या के आरोप के सिलसिले में नजरबंद रहे।

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

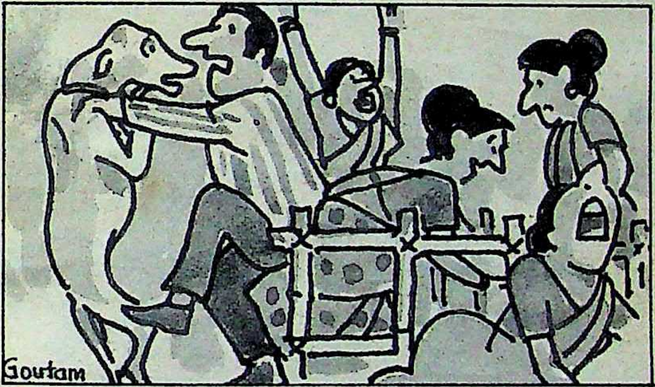

धांधली का रिकार्ड

लोकसभा और चार विधान-सभाओं के लिए २२ से २६ नवंबर तक तीन चरणों में संपन्न हुए चुनावों में जितने नये अजीबोगरीब वाकयात और नजारे नजर आये, उतने पहले कदाचित ही कभी देखने-सुनने में आये हों। इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाला नजारा निवर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय चुनाव क्षेत्र अमेठी ने पेश किया। यहां हिंसा, हुल्लड़बाजी और बूथ-कब्जे की घटनाओं ने राष्ट्र, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को ही नहीं बल्कि राजीव गांधी की सांस्कृतिक सलाहकार पुपुल जयकर को भी क्षुब्ध कर दिया। ९७ बूथों पर फिर से मतदान कराया गया। किसी एक संसदीय क्षेत्र में इतने बूथों पर पुनर्मतदान की दूसरी मिसाल नहीं मिलती, ना ही किसी प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र के इतने बदनाम होने की। मतदान के दिन कई बूथों पर तो मारधाड़वाली बबइया फिल्मों जैसी फायरिंग और हुल्लड़बाजी देखी गयी। ऐसी ही एक घटना में अमेठी विधानसभा सीट के जद प्रत्याशी संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये।

गड़बड़ी के सारे रिकार्ड तोड़ देनेवाले इन चुनावों में धांधली, बूथ-कब्जे में सबसे आगे रहा आंध्र प्रदेश। पूरे देश में जिन १४७५ बूथों पर फिर से मतदान कराये गये, उनमें से ५७६ मतदान केंद्र आंध्र के ही रहे। जिस पंजाब में हिंसा की सबसे अधिक आशंका थी वहां नहीं के बराबर हिंसा हुई जबकि २९ मौतों के साथ बिहार ने चुनावी रक्तपात का नया कीर्तिमान बनाया।

अंग्रेजी के चलते

अंग्रेजी के प्रति अपनी अवांछनीय ममता का खमियाजा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कर्नाटक की एक सभा में उस वक्त झेलना पड़ा जब अनुवाद न किये जाने के कारण उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोक देना पड़ा। स्थानीय नेता केसी शंकर गौड़ा द्वारा सही तर्जुमा न किये जाने पर जब सभा में शोरशराबा होने लगा, तब राजीव गांधी ने श्रोताओं से पूछा, "कैन यू ऑल फालो इंगलिश?" (क्या आप सब अंग्रेजी समझ सकते हैं?) इस पर श्रोताओं ने चुप्पी साध ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती मार्गरेट अलवा दूसरा अनुवादक तलाशने निकलीं, पर कोई मिला नहीं। मजबूरी में राजीवजी को गौड़ा के अनुवाद के साथ ही अपना भाषण पूरा करना पड़ा।

भिड़ंत से सांड़ भड़का

आंध्र प्रदेश में मचिलीपाटम के पास मालावोल गांव में दो दलों के समर्थकों में ऐसी भिड़ंत हुई कि उससे एक सांड बिदक गया और ६५ वर्ष के एक बूढ़े को अपनी सींगों से उछाल-उछाल कर मारने लगा। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को बाद में गुंटूर के सरकारी अस्पताल में भरती किया गया।

पुलिस, महिला और कुत्ता

शिमला प्वाइंट मतदान केंद्र पर उस वक्त अफरातफरी मच गयी जब एक पागल कुत्ता वोट डालने आयी महिलाओं के झुंड पर अचानक टूट पड़ा। वोटरों में भगदड़ मच गयी। भागती-पलाती दहशत की मारी औरतें एक दूसरी पर गिरती रहीं और पुलिस के जवान तमाशा देखते रहे। इस बीच एक युवक कुत्ते पर झपटा। दोनों में देर तक मल्लयुद्ध चलता रहा। अंतत: युवक ने कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया। पुलिसवाले तब भी तमाशा ही देखते रहे।

चुनाव में कबूतर

उड़ीसा पुलिस ने मतदान में मदद के लिए ६०० कबूतर लगा रखे थे। ये कबूतर हर तीन घंटे पर उड़ते और ४० मतदान केंद्रों का संदेश निकटतम थानों तक पहुंचाते रहे।

बकरी

अदीलाबाद संसदीय सीट (आंध्र प्रदेश) के निर्दल उम्मीदवार घनश्याम गुप्त की हार्दिक इच्छा रही की उनकी प्रचार-पदयात्रा में एक बकरी भी रहे। बकरी उनका चुनाव चिह्न थी। उन्होंने पदयात्रा में साथ रखने के लिए एक बकरी खरीद कर अपने युवा समर्थकों को दी भी। अगले दिन ही उनकी प्रचार-पदयात्रा थी। लेकिन पदयात्रा के ऐन वक्त वे यह देखकर अवाक रह गये कि बकरी मौके पर थी ही नहीं। बाद में पता चला कि पिछली रात में ही उक्त बकरी उनके समर्थकों का भोजन बन चुकी थी।

—वशिष्ठ मुनि ओझा

कार्टून : आरके मौर्य

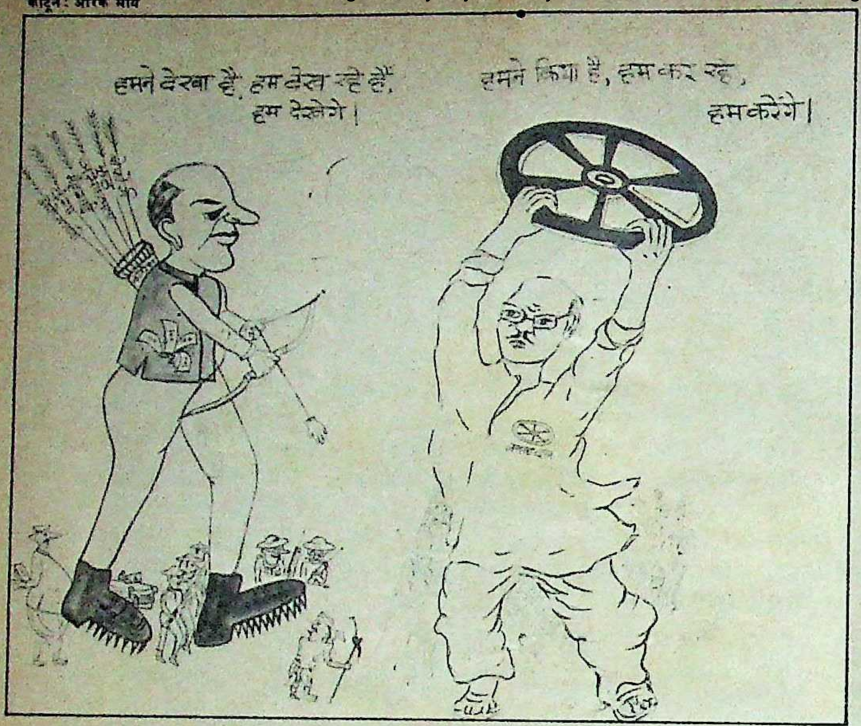
हमने देखा है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे।
हमने किया है, हम कर रहे, हम करेंगे।

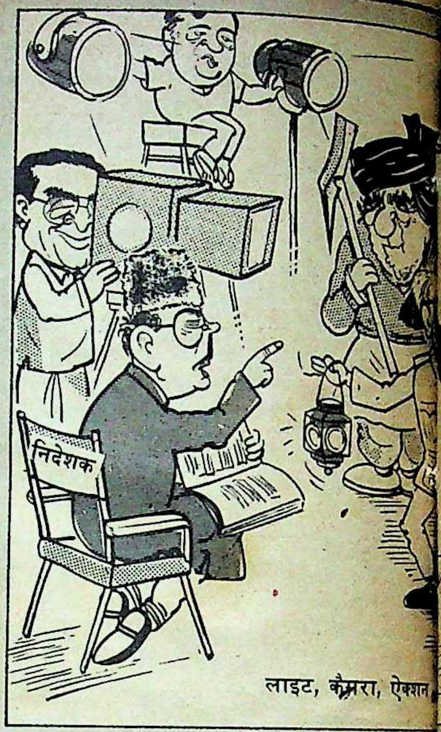

लाइट, कैमरा, ऐक्शन

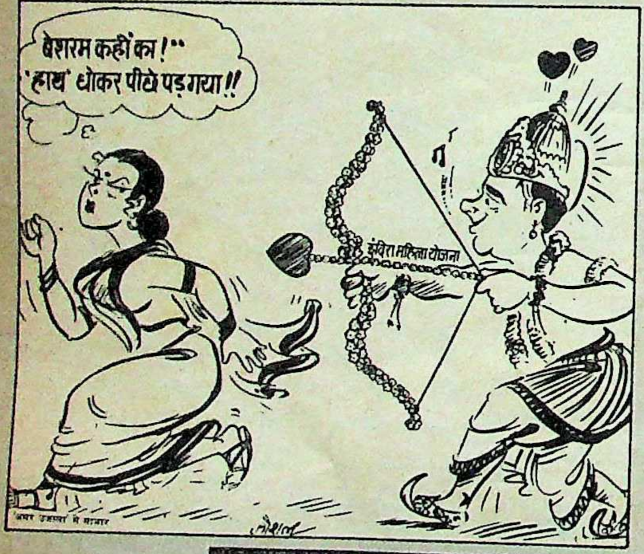
बेशरम कहीं का!" 'हाथ' धोकर पीछे पड़ गया!!
इंदिरा महिला योजना

'अमर उजाला' से साभार

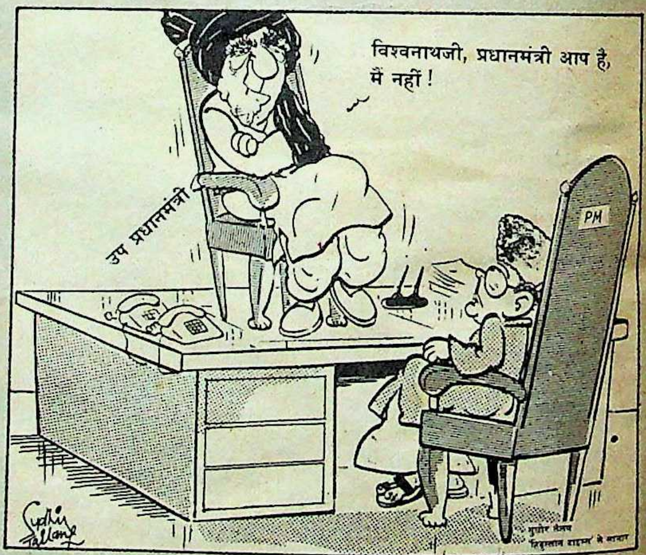
विश्वनाथजी, प्रधानमंत्री आप हैं, मैं नहीं!
उप प्रधानमंत्री
PM
Sudhir Tailang

सुधीर तैलंग
'हिन्दुस्तान टाइम्स' से साभार

महाभारत केसरी दंगल
मेरी शक्ति दलाली का पैसा अल्पमत तंत्र
हमारी शक्ति जनशक्ति और राष्ट्रप्रेम

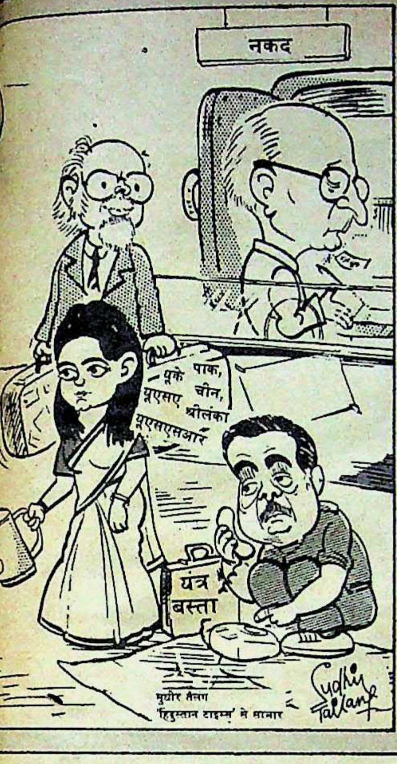
नकद
पूर्वे पाक,
यूएसए चीन,
श्रीलंका
यूएसएसआर
यंत्र
बस्ता
Sudhir Tailang

सुधीर तैलंग
'हिंदुस्तान टाइम्स' से साभार

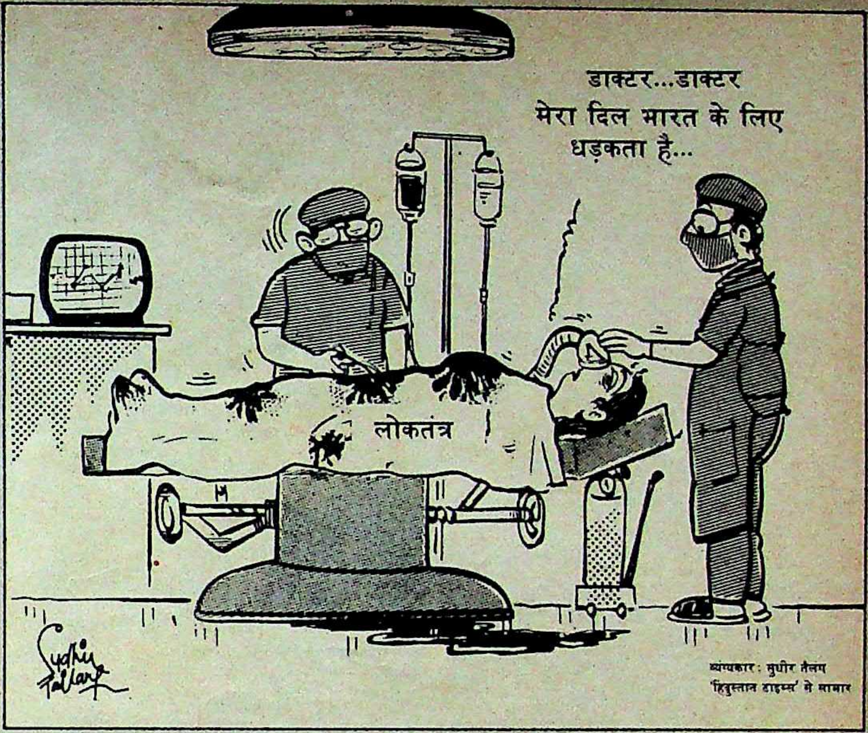
डाक्टर...डाक्टर
मेरा दिल भारत के लिए
धड़कता है...
लोकतंत्र
Sudhir Tailang

व्यंग्यकार: सुधीर तैलंग
'हिंदुस्तान टाइम्स' से साभार

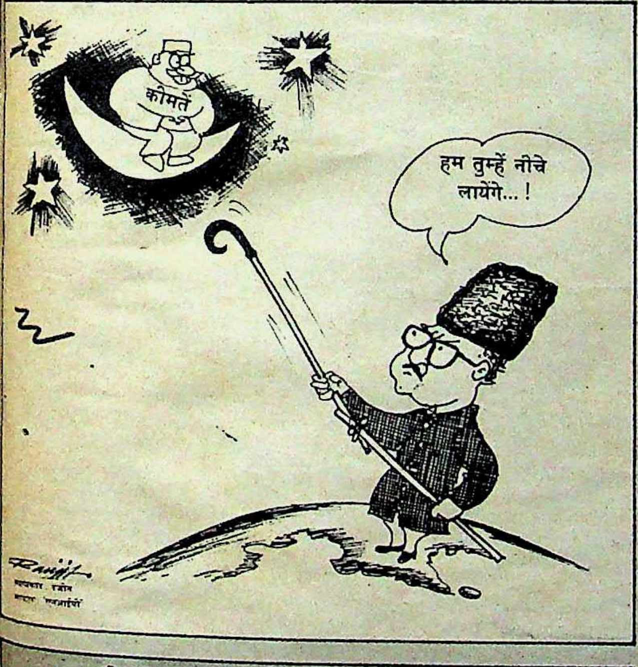
कीमतें
हम तुम्हें नीचे
लायेंगे...!
Ranjit

व्यंग्यकार: रंजीत
साभार: [illegible]

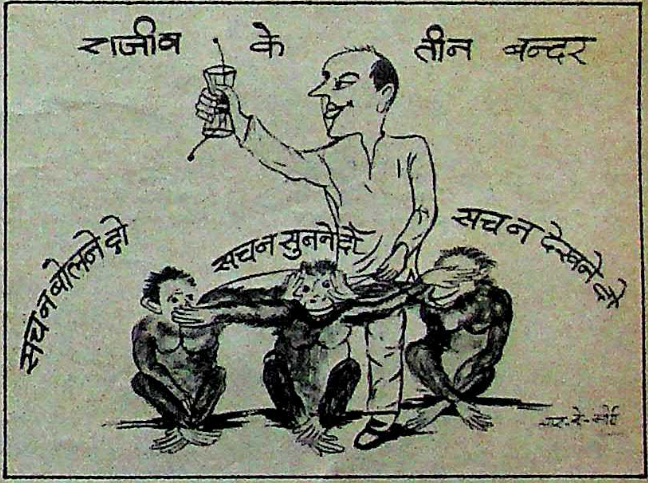
राजीव के तीन बन्दर
सच न बोलने दो
सच न सुनने दो
सच न देखने दो

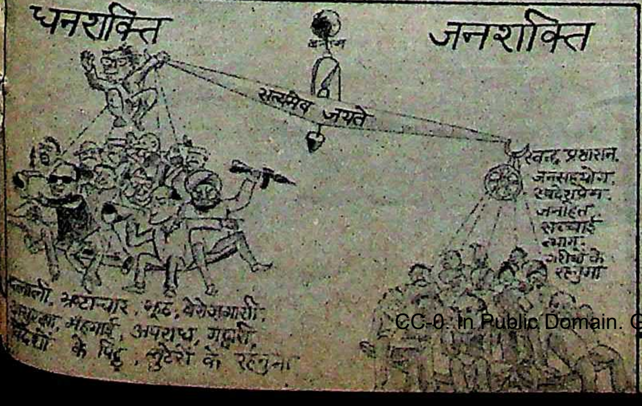
धनशक्ति
जनशक्ति
सत्यमेव जयते
स्वच्छ प्रशासन,
जनसहयोग,
स्वदेशप्रेम,
जनहित,
सच्चाई
त्याग,
गरीबों के
रहनुमा
...लाली, भ्रष्टाचार, झूठ, बेरोजगारी,
...सुरक्षा, महंगाई, अपराध, गद्दारी,
...विदेशों के पिट्ठू, लुटेरों के रहनुमा

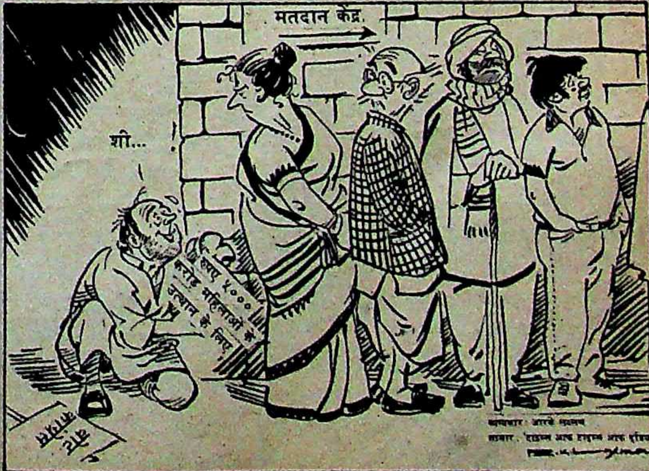
मतदान केंद्र
शी...
करोड़ रुपए ५००० महिलाओं के उत्थान के लिए

व्यंग्यकार: आरके लक्ष्मण
साभार: 'टाइम्स आफ इंडिया'

गोकुल सैकिया ने आत्महत्या क्यों की ?

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच २३ नवंबर को असम के लखीमपुर सीरी क्षेत्र के सांसद गोकुल सैकिया ने बिहार के प्रमुख तीर्थस्थल देवघर में पहुंचकर आत्महत्या क्यों की ? असम गण परिषद से निष्कासित किये जाने के बाद से वे अपने राजनीतिक कैरियर से हताश हो चुके थे या उनके परिवार में ही आत्महत्या की प्रवृत्ति रही है ?

एक तरफ जहां सारा देश लोकसभा चुनाव की सरगर्मी में था, वहीं असम में लोकसभा चुनाव न होने के कारण असम का राजनीतिक वातावरण बिलकुल शांत और ठंडा पड़ा हुआ था। पर उसी दौरान अचानक २३ नवंबर को असम के लखीमपुर सीरी क्षेत्र के सांसद गोकुल सैकिया द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने के समाचार ने संपूर्ण असम को स्तब्ध कर दिया। अटकलें गर्म होने लगीं कि आखिर गोकुल सैकिया ने आत्महत्या क्यों की और वह भी बिहार के प्रमुख तीर्थस्थल देवघर में जाकर ? अपने राजनीतिक जीवन में भी गोकुल सैकिया सदैव विवादों के घेरे में रहे। कभी असम गण परिषद से निष्कासित होने के कारण वे विवाद के विषय बने, तो कभी कार चोरी जैसी घटना में गिरफ्तार किये जाने के कारण विवादास्पद हुए। और अपने जीवन का अंत कर भी वे विवाद के विषय बन गये।

घटना : बिहार के प्रमुख तीर्थस्थल देवघर में चुनाव अभियान का सिलसिला २२ नवंबर की संध्या से ही थम गया था। २४ नवंबर को वहां चुनाव था। देवघर बांका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। देवघर की पुलिस और सारे प्रशासनिक अधिकारी चुनावी तैयारियों में मशगूल थे। अचानक २३ नवंबर को दिन के लगभग साढ़े नौ बजे देवघर में यह खबर आग की तरह फैल गयी कि देवघर के 'चेतना होटल' में गोकुल सैकिया नामक असम के एक सांसद ने आत्महत्या कर ली है। २१ नवंबर से गोकुल सैकिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 'चेतना होटल' के कमरा नंबर तीन में आकर ठहरे हुए थे।

गोकुल सैकिया

कभी असम गण परिषद से निष्कासित होने के कारण गोकुल सैकिया विवाद के विषय बने, तो कभी कार चोरी जैसी घटना में गिरफ्तार किये जाने के कारण।

२३ नवंबर को दिन के साढ़े नौ बजे चेतना होटल के मैनेजर सुशांत बनर्जी होटल में काउंटर की अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि उन्हें अचानक कमरा नंबर तीन से जोरों की चीख सुनाई पड़ी। सुशांत बुरी तरह घबड़ा उठे। जब सुशांत बनर्जी कमरा नंबर तीन में पहुंचे, तो देखा कि सांसद गोकुल सैकिया की पत्नी श्रीमती लुथफुन रसूल सैकिया बुरी तरह बिलख-बिलख कर चीख रही थीं—'गोकुल, दरवाजा खोलो।' बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद था और नल खुला होने के कारण पानी बहने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। होटल मैनेजर सुशांत बनर्जी ने भी बाथरूम के बंद दरवाजे को जोरों से पीटना शुरू किया, "खोलिए सर ! दरवाजा खोलिए। क्या हो गया आपको ?" पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पल भर में यह चीख-पुकार सुनकर होटल का पूरा स्टाफ उस कमरे में आकर जमा हो गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला, तो मैनेजर सुशांत बनर्जी थाने की तरफ दौड़ पड़े। वीआईपी का मामला था। 'चेतना होटल' से देवघर थाने की दूरी बहुत ज्यादा नहीं। उस समय थाने में थानेदार एकेपी पंकज संयोग से मौजूद थे। सुशांत बनर्जी को बदहवासी की स्थिति में देख थानेदार ने पूछा, "क्या बात है बनर्जी साहब, आप इतना घबड़ाये हुए क्यों हैं ?" थानेदार के इस सवाल पर सुशांत बनर्जी एक सांस में पूरी बात कह गये, "सर, हमारे होटल के कमरा नंबर तीन में पिछले दो दिनों से असम के सांसद गोकुल सैकिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठहरे हुए थे। अभी कुछ देर पहले सैकिया साहब की पत्नी जोरों से चिल्लाने लगीं। जब मैं वहां पहुंचा, तो वे बाथरूम का दरवाजा पीट रही थीं। बाथरूम में सैकिया साहब घंटों से बंद हैं। मुझे आशंका है कि बाथरूम में सैकिया साहब को कुछ हो तो नहीं गया। श्रीमती सैकिया एकदम से रो-रोकर बेहाल हैं। प्लीज, कुछ करिये।" मैनेजर सुशांत बनर्जी की बात सुन थानेदार एकेपी पंकज ने तत्काल अपने सहयोगियों को साथ लिया और सुशांत बनर्जी के साथ 'चेतना होटल' चल पड़े। होटल के गेट पर ही एक बैरे ने सुशांत बनर्जी को सूचना दी कि सैकिया साहब ने आत्महत्या कर ली है। बाथरूम में उनकी लाश पड़ी हुई है।

बहरहाल, सुशांत जब थानेदार को लेकर कमरा नंबर तीन में पहुंचे, तो पाया कि पूरा बाथरूम खून से लथपथ था और गोकुल सैकिया की लाश वहीं पड़ी हुई थी। थानेदार ने देखा कि गोकुल के गले पर जख्म के गहरे निशान हैं। फौरन उन्होंने बाथरूम की पूरी तलाशी ली, तो उन्हें एक नया उस्तरा हाथ लगा। इसी उस्तरे से गोकुल ने आत्महत्या की थी। थानेदार ने आगे की कार्रवाई के लिए उस उस्तरे को रूमाल में लपेटकर रख लिया। होटल से निकल कर तत्काल थानेदार ने इस हादसे की सूचना आरक्षी अधीक्षक तथा देवघर के उपायुक्त को दी। सूचना पाते ही तुरंत सारे अधिकारी चेतना होटल पहुंच गये। थानेदार ने जब गोकुल सैकिया की पत्नी के बारे में पूछा, तो पता चला कि वे थोड़ी देर पहले देवघर के 'अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम' गयी हैं। गोकुल सैकिया की बच्ची बाहर होटल के लान में खड़ी रो रही थी। पुलिस अधिकारियों के आदेश से होटल का एक कर्मचारी मृतक सांसद की पत्नी श्रीमती लुथफुन सैकिया को बुलाने 'अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम' की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद श्रीमती सैकिया 'अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम' के देवांशु शर्मा तथा तीन चार अन्य लोगों के साथ वापस होटल लौटीं। पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त के आदेश से गोकुल सैकिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए देवघर अस्पताल भेज दिया गया। देवघर के उपायुक्त एके पांडेय ने होटल से लौटकर इस घटना की सूचना असम सरकार के मुख्य सचिव तथा बिहार के गृह सचिव को फोन पर दी। बिहार के गृह सचिव ने फिर इस वाकये की सूचना लोकसभा के सचिव को फौरन भेज दी।

असम सरकार ने सूचना मिलते ही देवघर के उपायुक्त को खबर दी कि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद गोकुल सैकिया के शव सहित उनकी पत्नी और बच्चों को गाड़ी से कलकत्ता भेज दिया जाये और फिर कलकत्ता से असम सरकार के विमान द्वारा उनको गुवाहाटी ले जाया जायेगा। लिहाजा, पोस्टमार्टम के पश्चात देवघर के उपायुक्त ने पूरी

क्षा व्यवस्था के साथ गोकुल सैकिया की लाश हित उनकी पत्नी और बच्चों को कलकत्ता भेज या। २४ नवंबर की दोपहर साढ़े बारह बजे लकत्ता से असम सरकार के विमान से वे लोग वाहाटी चले गये। गोकुल सैकिया की आत्महत्या ने पूरे असम के लोगों को उत्सुक और परेशान कर दिया।

जीवन-वृत्त : गोकुल सैकिया का जन्म ९५१ में असम के लखीमपुर में हुआ था। गोकुल ार भाई थे। छात्र जीवन से ही गोकुल को ाजनीति में काफी दिलचस्पी थी। गोकुल के पिता ीना राम सैकिया को गोकुल का राजनीतिक तिविधियों में रहना पसंद नहीं था। बहरहाल, ीए करने के बाद गोकुल ने कानून महाविद्यालय जब दाखिला लिया, तो उनका परिचय असम ण परिषद के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत से हुआ। र गोकुल प्रफुल्ल महंत के अत्यंत निकट आते ये और असम गण परिषद द्वारा चलाये जा रहे ांदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगे। ांदोलन के दिनों में ही गोकुल की मुलाकात एक ड़की लुथफुन से हुई। लुथफुन उन दिनों कानून ी पढ़ाई कर रही थी। १९७८ में गोकुल ने ुथफुन से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ीमती लुथफुन सैकिया को असम में ही व्याख्याता ी नौकरी मिल गयी। प्रफुल्ल महंत ने आंदोलन गोकुल सैकिया की सक्रियता से प्रसन्न होकर खीमपुर सीरी संसदीय सीट से गोकुल को असम ण परिषद का उम्मीदवार बनाया। गोकुल ैकिया वहां से भारी मतों से जीते।

सांसद बनने तक गोकुल दो बेटियों के पिता ी हो गये थे। उनकी बड़ी बेटी कस्तूरी गोकुल भी नौ साल की है और छोटी बेटर कृष्णा गोकुल ाच साल की। दिल्ली में गोकुल को साउथ एवेन्यू २६ नंबर का क्वार्टर मिला जहां वे सिर्फ ंसदीय सत्र के दौरान रहते थे। ज्यादातर गोकुल ुवाहाटी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, क्योंकि ौकरी में रहने के कारण लुथफुन सैकिया स्थायी प से दिल्ली जाकर नहीं रह सकती थीं।

मनमुटाव : १९८६ में गोकुल सैकिया का ुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ हयोगियों से गंभीर मनमुटाव हो गया। रअसल, गोकुल पर असम गण परिषद के अन्य ेता आरोप लगा रहे थे कि गोकुल पार्टीविरोधी तिविधियों में सक्रिय रहते हैं। उनके खिलाफ ार्रवाई हुई, अंततः गोकुल पार्टी से निष्कासित र दिये गये। पार्टी से निकाले जाने के बाद गोकुल मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। उनके अंतरंग मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि मन की शांति के लिए े बिहार के देवघर स्थित 'अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम' जायें और दीक्षा लें। १९८७ में गोकुल ने पत्नीक सत्संग आश्रम जाकर दीक्षा ली। फिर वे र साल देवघर आकर सत्संग आश्रम के कार्यक्रमों ं भाग लेते रहे।

गोकुल ने हताश होकर आत्महत्या की : दीनानाथ शर्मा

कार चोरी का इल्जाम : १९८९ में गोकुल सैकिया के साथ एक और विवादास्पद घटना घटी। १६ जून, १९८९ को असम की तेजपुर पुलिस ने गोकुल सैकिया को कार चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एएमवाई २८६७ नंबर की वह कार असम के लघु सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष नागेन गोगोई की थीं। धारा—३७९ के तहत तेजपुर के चांदमारी पुलिस स्टेशन में गोकुल के खिलाफ कार चोरी का मामला दर्ज हुआ और गोकुल गिरफ्तार कर लिये गये। पांच दिनों तक हवालात में बंद रहने के बाद सांसद गोकुल सैकिया मानसिक रूप से और भी विचलित हो उठे। वे बाहर तो परेशान थे ही घरेलू कारणों से भी कम परेशान नहीं थे। पत्नी लुथफुन से भी उनका बराबर तनाव रहता था। मानसिक शांति के लिए ही २० नवंबर को गोकुल सैकिया सपरिवार देवघर गये थे। देवघर आने पर आमतौर पर वे देवघर के सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरा करते थे। पर इस बार चुनाव के कारण सरकारी निरीक्षण भवन में जगह न मिलने की वजह से वे 'चेतना होटल' में ठहरे। चेतना होटल के मैनेजर सुशांत बनर्जी के अनुसार २१ नवंबर की संध्या को गोकुल सैकिया चेतना होटल आये। कई कमरों को देखने के बाद उन्होंने कमरा नंबर तीन को पसंद किया। शाम को छह बजे थोड़ी देर के लिए वे सपरिवार कहीं निकले, फिर अगले दिन २२ नवंबर को गोकुल सपरिवार सत्संग आश्रम गये। घटना के दिन यानी २३ नवंबर को सुबह आठ बजे पत्नी-बच्चों सहित गोकुल सैकिया कमरे से बाहर आये। आगे-आगे स्वयं गोकुल अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़े चल रहे थे और पीछे पत्नी लुथफुन थीं। पत्नी ने काउंटर पर रेलवे की समय-सारिणी मांगकर देखी और पूछा कि दिल्ली जाने के लिए दिन में कौन-कौन सी ट्रेन है? इतना पूछने के बाद गोकुल, लुथफुन और बच्चे वापस कमरे में चले गये। लगभग डेढ़ घंटे बाद ही श्रीमती लुथफुन सैकिया की चीख कमरे से आने लगी।

देवघर अनुकूल चंद्र आश्रम के दीनानाथ शर्मा मूलतः असम के हैं और आश्रम में ऋत्विक के पद पर हैं। असमवासी होने के कारण ही दीनानाथ से गोकुल की निकटता भी थी। दीनानाथ कहते हैं कि इधर काफी दिनों से वे मानसिक रूप से विचलित चल रहे थे। वे अकसर कहते थे कि जीवन में मैंने बहुत पाप किया है और उसका प्रायश्चित मुझे करना है। उनकी बेटी कस्तूरी की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। गोकुल कहते थे कि उनके पाप का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है। २३ नवंबर को ही उनकी पत्नी का जन्मदिन था। उन्होंने कहा था कि पत्नी का जन्मदिन वे सत्संग आश्रम में ही आकर मनायेंगे। पर उसी दिन उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया।

लुथपुन का जवाब : देवघर पुलिस को अपने लिखित बयान में श्रीमती लुथफुन सैकिया ने बताया, "मेरे पति की नाक से २३ नवंबर की सुबह थोड़ा खून निकला था। इसके लिए वे डाक्टर से मिलने गये थे। फिर उन्होंने कहा कि तुरंत सामान बांधो, आज ही सत्संग आश्रम से लौटने के बाद हम लोग दिल्ली चलेंगे। यह कहकर वे बाथरूम चले गये। थोड़ी देर बाद बाथरूम से उनकी बुरी तरह कराहने की आवाज आने लगी। अंदर नल का पानी उन्होंने काफी तेज चला दिया था। काफी देर तक बाथरूम से वे नहीं निकले, तो मुझे चिंता हुई। दरवाजा तोड़ा गया, तो बाथरूम से उनकी लाश निकली।" देवघर पुलिस ने श्रीमती लुथफुन सैकिया के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया (केस नंबर २७/८९)। गोकुल अपनी राजनीतिक स्थिति से भी परेशान थे। उन्हें आशंका थी कि अगले संसदीय चुनाव में वे नहीं चुने जा सकेंगे। अनुकूल चंद्र आश्रम के दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि गोकुल अकसर हताश होकर कहा करते थे कि राजनीति में मुझे लोगों ने बहुत 'चीट' किया। असम गण परिषद से निष्कासित किये जाने की बात को लेकर भी वे बुरी तरह आहत थे। मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा नोटबुक पर हाथी का चित्र अंकित करना शायद उनकी इस तकलीफ को जाहिर करता है। हाथी असम गण परिषद का चिन्ह है। उसके ठीक बगल के पृष्ठ पर उन्होंने पत्नी तथा बच्चों के नाम यह पंक्ति भी लिखी है, "स्ली, कस्तूरी, कृष्णा मुझे माफ मत करना!"

पर क्या गोकुल की आत्महत्या सिर्फ उनकी राजनीतिक हताशा का ही परिणाम है? गोकुल की पत्नी ने देवघर पुलिस को बताया कि कुछ वर्ष पहले गोकुल की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसलिए क्या गोकुल सैकिया के परिवार में ही आत्महत्या की प्रवृत्ति थी? आत्महत्या के बाद ये और ऐसे अनेक सवाल गोकुल सैकिया छोड़ गये हैं।

—विकास कुमार झा

—छाया : सजीव बनर्जी

—ममता कालिया

चुनाव में हिंसा, हिंसा में चुनाव

विपक्ष के सबसे बड़े लोकतंत्र की जन-ऊर्जा का विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे उपयोग करेंगे, यह तो समय बतायेगा, इससे भी ज्यादा जिज्ञासा इस बात की है कि वे विपक्ष के साथ कैसा आचरण करेंगे। क्या इस चुनावी संघर्ष को सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध जैसा कोई महान आयाम तथा समापन दिया जायेगा अथवा सन् १९७७ के चुनाव के पश्चात जैसा घात-प्रतिघात और आघात का दुष्चक्र चलाया जायेगा।

अभी कल तक जब भी कहीं गोली चलती, लाठी तनती या बम फटता, शासन उसे आतंकवादियों के मत्थे मढ़ कर खुद निष्कलंक बना रहता अथवा यह बयान जारी कर देता कि लगता है पाकिस्तान अथवा विपक्ष के लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु इस आम चुनाव में यह भलीभांति स्पष्ट हो गया कि हिंसा केवल आतंकवादियों का महकमा नहीं। जिसको जब इसकी जरूरत पड़ती है, वह इसका सहारा लेने में परहेज नहीं करता। जनता दल महासचिव संजय सिंह पर हुआ कातिलाना हमला इसका सबसे ताजा सबूत है। दुख और हैरानी की बात है कि यह हमला उस इलाके में हुआ जो राजीव गांधी का चुनाव-क्षेत्र है और जहां के बारे में अब तक कुछ इस तरह प्रचारित किया जाता रहा कि मुल्क में अगर कहीं जन्नत है, तो बस अमेठी में। अमेठी के कांग्रेसी रहनुमा बराबर कहते रहे कि अमेठी में रामराज्य है। वहां पुलिस का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां सब लोग बारोजगार हैं, वहां विकास है, वहां प्रकाश है, वहां खुशी और खुशहाली की बरसात है। लगता है बाईस नवंबर के रोज वहां पुलिस और प्रशासन को वाकई कोई काम नहीं था, ये दोनों विभाग सोये पड़े थे जो संजय सिंह जैसे धाकड़ जननेता को बाकायदा घेर कर घायल किया गया। बजाय इसके कि इस वारदात की निष्पक्ष जांच करायी जाये, पक्ष के प्रवक्ता घिनौनी दलीलें देने में लगे रहे कि यह संजय सिंह का अपने ही दल के लोगों के साथ आपसी संघर्ष था अथवा उन्होंने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवा ली। इन मासूम प्रवक्ताओं को इतना भी नहीं पता कि कोई भी चुनाव प्रत्याशी इतना मूर्ख या धूर्त नहीं होता कि जान पर खेल कर अपने लिए राजनीतिक हमदर्दी जुटाये, खास तौर पर तब, जब अपने चुनाव क्षेत्र में उसका दबदबा पहले से हो और राजनीति में वह अपनी जगह बना चुका हो।

इस खतरनाक हमले का शर्मनाक पहलू यह है कि सिर्फ एक उम्मीदवार का हक छीनने की नीयत से ऐसा नहीं किया गया, वरन् विपक्ष की आवाज का गला घोंटने के लिए ऐसा किया गया। लोकतंत्र की सफलता में पक्ष के साथ-साथ सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका अनिवार्य है। किसी भी पक्ष को यह अधिकार तो है कि वह अपने विपक्षी को हरा दे, किंतु यह अधिकार नहीं है कि उसे गोली मार दे। जब भी कहीं कोई प्रत्याशी एक शक्तिशाली चुनौती बनने लगता है, वहां हिंसा का क्रूर चेहरा बेनकाब होने लगता है। कहीं प्रत्याशी चोट खाता है, तो कहीं मासूम जनता। ऐसा कैसे मान लिया जाये कि समूचे देश में कुछ लोग अपने पेट में गोली मार रहे हैं, महज हमदर्दी का वोट बटोरने के खातिर।

अब जब संयुक्त मोर्चा चुनाव जीत गया है, यह प्रश्न उठाना निहायत जरूरी है कि इस बिंदु से भारतीय राजनीति में क्या मूल्यपरक दृष्टि का सूत्रपात होगा। मानवीय मूल्यों की बात साहित्य, संस्कृति और कला के संदर्भ में की जरूरी रही है, कुछ इस तरह, जैसे महज ये तीन, मानव मूल्यों के महकमे हैं। राजनीति के क्षेत्र में इसकी जरूरत पर विचार-विमर्श आजादी मिलने के बाद से ही गैरजरूरी समझा गया है। महात्मा गांधी साधन और साध्य की शुद्धता पर विशेष जोर देते थे। संयुक्त मोर्चे ने अपने चुनावी अभियान का आधार इसी शुद्धीकरण को बनाया और चुनाव जीत लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोगों के दिल-दिमाग में यह बात पक्की तौर पर बिठा दी कि कांग्रेस के पास भ्रष्ट साधनों की दुष्ट ताकत है। उन्होंने पैदल चल कर, साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव का दौरा किया, जहां पहुंचे वहां के रहनेवालों की जुबान में अपनी बात समझायी और देश में एक बार फिर गांधीवाद की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस के चुनाव अभियान की चकाचौंध से बौखलाए लोगों को उनकी सीधी-सादी बातें साफ समझ में आयीं और देखते-देखते पहिया, परिवर्तन का प्रतीक चिह्न बन गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो गये, लेकिन एक दूसरे जननेता की तरह उन्हें पता होगा कि चोटी से ही रास्ता ढलान की ओर जाता है। नये प्रधानमंत्री को सबसे पहले जनता की उम्मीदों को पूरा करने का कोई कारगर तरीका ढूंढ़ना होगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जन-ऊर्जा का विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे उपयोग करेंगे, यह तो समय बतायेगा, इससे भी ज्यादा जिज्ञासा आज इस बात की है कि वे जो कल तक विपक्ष में थे, आज पक्ष में बैठ कर अपने विपक्ष के साथ कैसा आचरण करेंगे। क्या इस चुनावी संघर्ष को सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध जैसा कोई महान आयाम तथा समापन दिया जायेगा अथवा सन १९७७ के चुनाव के पश्चात जैसा घात-प्रतिघात और आघात का दुष्चक्र चलाया जायेगा। दूसरी स्थिति में नवनिर्मित पक्ष अपनी शक्ति का काफी अपव्यय कर बैठेगा और वह जन साधारण जिसकी आंख में क्रांति का अंजन आंज कर उसने परिवर्तन का वादा किया था, एक बार फिर पीड़ित ही रह जायेगा। नये प्रधानमंत्री से लोगों को मूल्यपरक नेतृत्व की प्रबल प्रतीक्षा है। ■

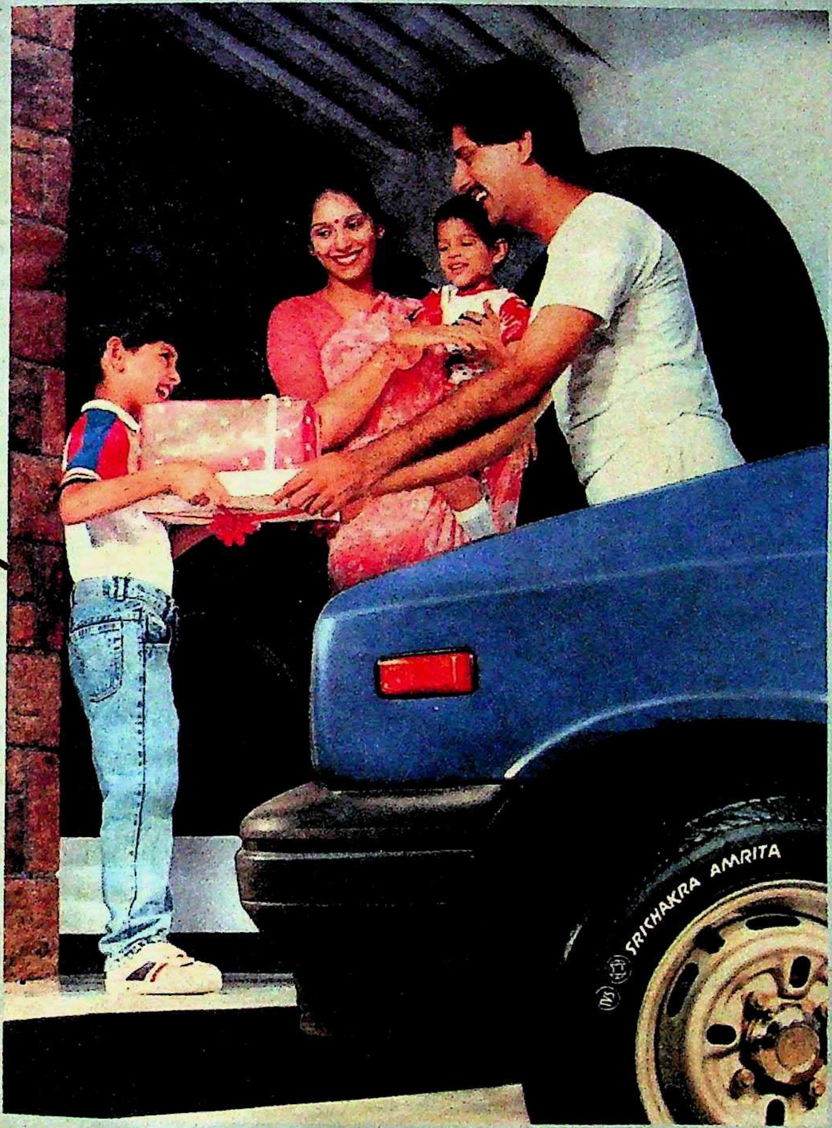

डैडी लौट आए सही-सलामत मेरे जन्मदिन पर...

७ बज चुके थे.
हम लोग अभी भी इन्तज़ार कर रहे थे.
डैडी का. क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद उनके
घर लौटने का.

मम्मी बोलीं, "मुझे तो घबराहट हो रही है.
डैडी को लम्बा रास्ता तय करना है.
इतनी दूरी और उसपर से इतनी
खराब सड़कें."

अनिरुद्ध तो रोने ही लगा.

मुझे भी चिन्ता होने लगी.

तभी सहसा हॉर्न सुनाई दिया.
और डैडी आ गए, सही सलामत:
मेरे लिए ढेर सारे तोहफ़े लेकर.
मज़ा ही आ गया. जन्मदिन क्या खूब मना!

**टी वी एस श्रीचक्रा टायर्स.
गीली और सूखी सड़कों पर
बेहतर पकड़.
कोनों-किनारों पर बेहतर नियंत्रण.
सड़क पर बेहतर पकड़.
बेहतर...क्योंकि यह
टी वी एस का है.**

'LOCK-IN' TREAD FOR ADDED SAFETY

सुरक्षा ऐसी कि आप पूरा भरोसा कर सकें. श्रीकांत तो करते हैं.

TVS SRICHAKRA TYRES

R K SWAMY/STU/7415/HIN

11151

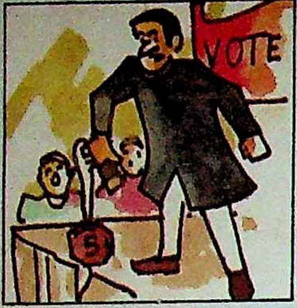

जो कहोगे, करूंगा

अभी तक नेतागण आम मतदाताओं को बुद्धू समझते रहे हैं, लेकिन ८९ के आम चुनाव में मतदाताओं ने नेताओं को यह बता दिया कि बुद्धू वे नहीं नेता हैं। मतदाताओं ने उनके सामने ऐसी-ऐसी शर्तें रखीं कि वे बेचारे पानी मांग गये। कहीं कुछ निर्दल उम्मीदवारों से जनता ने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे, तो कहीं बिजली के खंभे पर चढ़ने के लिए कहा, कहीं उनको कलाबाजियां दिखाने को मजबूर किया, तो कहीं 'इस हाथ पानी, उस हाथ वोट' के नारे लगाये। वाराणसी जिले के बड़ागांव बाजार में तो श्रोताओं ने एक प्रत्याशी को भाषण ही नहीं देने दिया। वहां उपस्थित सभी श्रोता उत्तेजित हो गये और कहने लगे कि नेताजी ने चूंकि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम उन्हें बोलने नहीं देंगे। यदि नेताजी पांच किलो के बटखरे से बंधा माइक हाथ में लेकर भाषण करें, तो वे उन्हें बोलने देंगे। इस प्रस्ताव पर आम सहमति हुई और नेताजी ने माइक में पांच किलो का बाट बांधकर भाषण शुरू किया, लेकिन बेचारे पांच मिनट से अधिक माइक संभाल ही नहीं पाये।

भुतहा मंच

कोई-कोई स्थान ऐसा शुभ और अशुभ होता है कि उससे जीत-हार का संबंध जुड़ जाता है। चुरू स्थित लोहिया कालेज मैदान में बना चुनावी मंच इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इस मंच से जिस नेता ने भाषण दिया, वह या तो चुनाव हार गया या वह पद से हाथ धो बैठा।

१९७७ में कांग्रेस की चुनावी सभा के लिए बने इस मंच से इंदिरा गांधी ने मोहम्मद उस्मान आरिफ के पक्ष में भाषण दिया था। आरिफ तो चुनाव हार ही गये, इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। १९८० के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इसी मंच से भाषण दिया था, बाद में वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसी प्रकार त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नृपेंद्र चक्रवर्ती ने भी इसी मंच से बोलने के बाद अपना मुख्यमंत्री पद खोया था। १९८४ में शिवचरण माथुर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में इसी मंच से भाषण दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ४ नवंबर को इसी मंच से इंका प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में भाषण दिया।

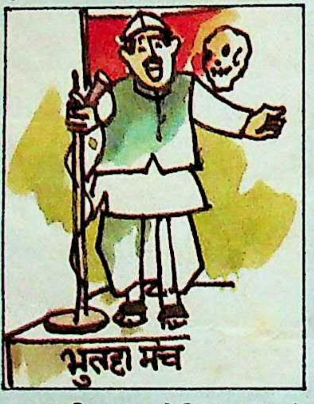

पियक्कड़ो एक हो !

इस चुनाव में जिस तरह एक-से-एक अजीबोगरीब प्रत्याशी मैदान में थे, उसी तरह राष्ट्रीय पार्टियों के बरक्स कई पार्टियां भी चुनावी महासमर में थीं।

यदि अवसरवादी दल अपना समर्थन सारे अवसरवादी प्रत्याशियों को दे रहा था, तो 'शराबी कांग्रेस' ने अपने एकमात्र प्रत्याशी रामस्वरूप को जम्मू निर्वाचन क्षेत्र से छठी बार खड़ा किया था। रामस्वरूप का कहना है, "राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस असली कांग्रेस नहीं है, क्योंकि इसके कई नेता मदिरापान करते हैं।" रामस्वरूप ने कांग्रेस-इ के नेताओं से अपील भी की थी कि यदि वे रोजाना केवल एक भी 'पैग' पीते हों, तो भी उनकी पार्टी में उनका स्वागत है। रामस्वरूप के ऊपर हार या जीत का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक मात्र उद्देश्य शराबियों की एकता है।

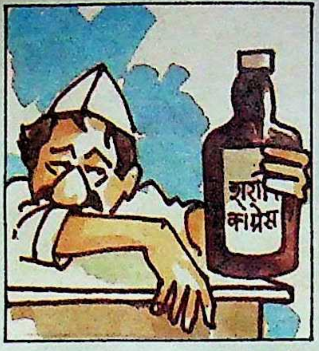

रोजाना १५ पैग पीने का दावा करनेवाले रामस्वरूप ने अपने घोषणा-पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि यदि वे जीत गये, तो लोकसभा में शराबियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। रामस्वरूप का चुनावी अभियान भी अनोखा था। वे रोज शराब की दुकान पर बैठ जाते थे और हर पियक्कड़ से वोट की प्रार्थना करते थे।

सोहबत का असर

सोहबत का ऐसा असर होता है कि कुछ लोग सोहबत के चलते बड़े-से-बड़ा काम कर डालते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। सासाराम के एक निर्दल प्रत्याशी को ऐसी ही स्थिति से दो-चार होना पड़ा।

नोखा थानांतर्गत सीसरित निवासी गया दुबे ने गेहूं बेचकर विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र से परचा भरने के लिए ५०० रुपए जुटाये थे। गांव में ही स्थित एक धर्मशाला के पास चौपाल में बैठे जुए की फड़ पर तमाशा देखने के लिए वे रुके ही थे कि इसी बीच पुलिस आ गयी। उस धाधे में वे यह नहीं बता पाये कि वे नेता हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फलस्वरूप पुलिस ने अन्य जुआड़ियों के साथ दुबे को भी जेल के अंदर कर दिया। उन्होंने पुलिसवालों से बड़ी गुजारिश-मिन्नत की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। दुबे के पैसे तो गये ही, वे परचा भरने से भी रह गये। बाद में एक नेता की वजह से वे जमानत पर छूटे।

VOTER
Goutam ch

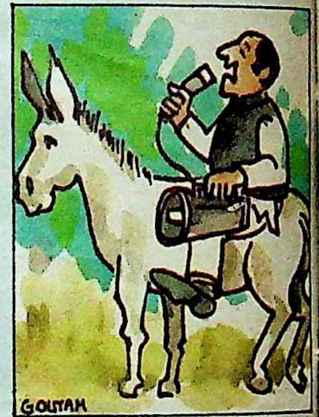

गधे पर प्रचार

जहां कांग्रेस ने इस चुनावी अभियान में करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर स्वाहा कर दिये तथा अरुण नंदा की कितनीं ही रातों की नींदें हराम हुईं, वहीं राजस्थान में रूपनगढ़ कस्बे में नोरत खटीक ने कांग्रेस का चुनावी प्रचार अनोखे ढंग से, किंतु बिना एक पाई खर्च किये किया। वे गधे पर तिरंगे झंडों के साथ बैठकर कांग्रेस-इ के प्रत्याशी गोवि सिंह गुर्जर के पक्ष में वोट मांग रहे थे। एक दिन केंद्रीय कपड़ा मंत्री रामनिवास मिर्धा ने जब उसे गधे पर सवार हो कांग्रेस का प्रचार करते देखा, तो उनको बड़ा दुःख हुआ तथा उन्होंने इस प्रकार चुनाव प्रचार के लिए उसे मना किया। लेकिन उसने छूटते हुए कहा कि उसका तो यही वाहन है। यदि उन्हें बुरा लगता है तो वे उसके लिए एक जीप की व्यवस्था कर दें।

—डा॰ मुश्ताक अल

साड़ियों के नये-नये रंग
यू.पी. हैण्डलूम के संग

- बनारसी रेशमी साड़ियां (ब्रोकेड एवं तनछुई)
- चन्देरी, सिल्क शिफान, क्रेप ज्ञिसीन, इम्बास
- हाथ की बनी हुयी पालिएस्टर ब्लेण्डेड साड़ियां
- सूती, चिकन एवं कटवर्क साड़ियां

हमारे निम्न शो रूम में पधारकर अपना संरक्षण प्रदान करें

- नई दिल्ली 'अरबिन्दो प्लेस' हौजखास, खान मार्केट
- आगरा-संजय प्लेस
- लखनऊ-मेफेयर बिल्डिंग
- कानपुर-पी.पी.एन. मार्केट
- इलाहाबाद-सिविल लाइन्स
- वाराणसी-नीचीबाग
- जयपुर- एम.आई.रोड
- चण्डीगढ़-सेक्टर १७ सी.
- भोपाल-टी.टी. नगर,
- बम्बई-कोलाबा
- कलकत्ता-लिन्डसे स्ट्रीट
- मद्रास-माउण्ट रोड
- बिहार-पटना, रांची, जमशेदपुर
- म.प्र. जबलपुर

तथा सारे देश में फैले हुए १५० अन्य शो रूम

HANDLOOMS

यू.पी. हैण्डलूम्स

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
हथकरघा भवन जी.टी.रोड, कानपुर, उ.प्र.

रेखा का भ्रष्टाचार

कौन कहता है कि गहरे रंग के चश्मे के भीतर छिपी सितारों की निगाह खोजी पत्रकारों की निगाहों से कम तेज होती है। १८ हजार रुपए का कीमती चश्मा लगाये रेखा की निगाहें सड़क पर टंगे एक पोस्टर पर कुछ ऐसी चस्पां हुई कि उन्हें हटाने के लिए आनन-फानन निर्माता-निर्देशक रमेश सिप्पी को भाग कर वहां पहुंचना पड़ा। उन्होंने इस पोस्टर को न केवल उसी समय वहां से हटवा दिया, बल्कि उन्हें अपने आदमियों को तुरंत पूरी बंबई में लगे अपनी फिल्म 'भ्रष्टाचार' के सभी पोस्टर उतरवाने का हुक्म देना पड़ा और फिल्म की तयशुदा प्रदर्शन-तिथि रद्द कर आगे के लिए मुल्तवी करानी पड़ी। दरअसल, हुआ यह कि एक दिन शूटिंग के लिए जाते समय रेखा, जो 'भ्रष्टाचार' में खोजी पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं, की निगाह 'भ्रष्टाचार' के विशालकाय पोस्टर पर पड़ी। किसी मनचले ने पोस्टर पर बड़े-बड़े हर्फों में लिखे 'रमेश सिप्पीज भ्रष्टाचार विद रेखा ऐंड मिथुन चक्रवर्ती' में थोड़ा-सा परिवर्तन कर उसे यों बना दिया था—'राजीव गांधीज भ्रष्टाचार विद वीपी सिंह ऐंड अरुण नेहरू'।

अनुराधा का सच

निर्माता-निर्देशक-अभिनेता विनोद पांडे के 'सच' ने अमिताभ के 'सच' को मुसीबत में तो डाल ही दिया था, अब उनकी नायिका अनुराधा सावंत ने सभी ग्लैमरस अभिनेत्रियों के सामने परेशानी पैदा कर दी है। परेशान तो सेंसर बोर्ड भी है— अनुराधा के बेहद उत्तेजक एवं अंग-प्रदर्शनवाले दृश्यों को लेकर। २० वर्षीया अनुराधा ने जवान बेटे-बेटियोंवाली एक ऐसी मां की निभायी है, जो अपने खा संत्रस्त हो दूसरे ऊबे हुए वि पुरुष से खुलेआम शारीरि रखकर समाज और नैतिक मू विरुद्ध विद्रोह कर बैठती है।

उत्तेजक अंग-प्रदर्श तथा अधेड़ उम्र की महि भूमिका निभाने से उसे हर बरजा, लेकिन अनुराधा ने यह कहते हुए विद्रोह किया, " का थोड़ा-सा अंग दिखला ज्यादा दिखलाना— इसमें फ पड़ता है, बशर्ते वह अश्लील हद तक न हो। मैंने अपने कि साथ न्याय किया है, उन लो तरह दोहरी नैतिकता नही दि है, जो करते तो सब कुछ हैं, नैतिकता के लबादे में उसे ढं भी कोशिश करते हैं।"

लेकिन अनुराधा की मु यह है कि अब हर निर्माता उस ही सीन कराना चाहता है।

साबिया : दुस्साहस की सजा

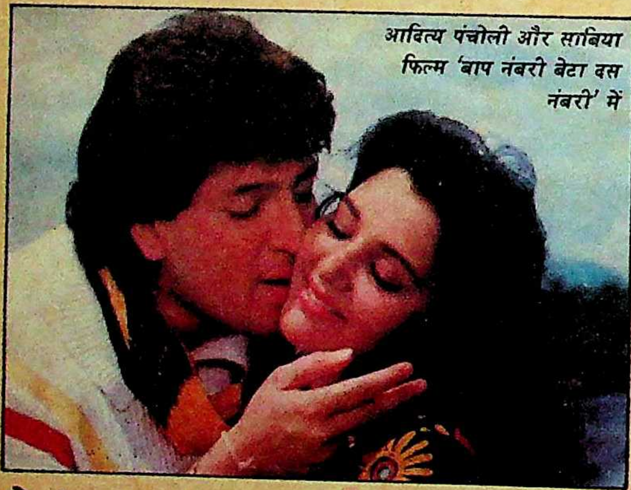

आदित्य पंचोली और साबिया फिल्म 'बाप नंबरी बेटा दस नंबरी' में

दो वर्ष पहले नयी अभिनेत्री साबिया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना की आबरू को सरेआम खतरे में डाल दिया था, तब उसे पता नहीं था कि उसके इस दुस्साहस और बेबाक बयानबाजी का क्या खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। राजेश खन्ना के विरुद्ध दिये गये बयान ने उसे सुर्खियों की रानी तो बना दिया था, लेकिन इसके बाद कोई भी कलाकार उसके साथ काम करने के लिए तैयार नही हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि साबिया स्टार बनते-बनते रह गयी और उसकी जगह सोनम और माधुरी दीक्षित ने हथिया ली। लेकिन फिलहाल आदित्य पंचोली उसकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए जिससे साबिया को 'बाप नंबरी बेटा दस नंबरी' में रोमांटिक लीड मिल गयी है। लेकिन साबिया ने कुछ भी बोलने से पहले बीस बार सोचने और नजरअंदाज कर देने की कला जरूर सीख ली है।

◆

मिथुन का जिगर

111151

अब यह तो मिथुन के ही जिगर की बात है कि १९८९ का सर्वाधिक 'फ्लाप हीरो' का तमगा पाने के बावजूद अपनी (ना) कामयाबी का शानदार जश्न मनाया—मामूली-से-मामूली पत्रकार को खुद फोन कर सपरिवार पार्टी में आमंत्रित किया, उनके साथ चित्र खिचवाये फिर अलग-अलग डिनर पर आमंत्रित किया। लेकिन खा-पीकर भी पत्रकार अपनी शैतानी से बाज नहीं आये। एक ने आखिर पूछ ही लिया, "आपने यह पार्टी जिस फिल्म के सिलवर जुबली हिट होने के एवज में दी है, उसका तो नाम भी हमने नहीं सुना। भला, वह रिलीज कब हुई थी?"

शायद मिथुन को भी इसका पता नहीं था, सो कान खुजाते हुए उन्होंने उस फिल्म के निर्माता ओर देखा। अब निर्माता कुछ इसके पहलें नीलम टपक पड़ीं, हुआ, तो हो जायेगा। वैसे मि 'प्यार' शब्द वाले जिस भी फि काम करते हैं, वह तो हिट हो है। मिथुन की 'प्यार झुकता सुपरहिट हुई थी कि नहीं?" न फिल्म 'प्यार का कर्ज' में मिथु हीरोइन है और जिस फिल्म शानदार सिलवर जुबली पार्टी मिथुन ने अपनी गांठ से दी थी थी—'प्रेम प्रतिज्ञा'। अब यह दूसरी है कि १९८९ में मिथुन लगभग दो दर्जन फिल्में रिली और एक ही हफ्ते में उतर भी ग

—अखबारी

मिथुन चक्रवर्ती और नी

Compiled
[illegible]-2019

111151